

आधुनिक शासन-तन्त्र [सिद्धान्त एव व्यवहार]

MODERN GOVERNMENTS [THEORY AND PRACTICE]

लेखक भद्रदत्त शर्मा एम ए (इति एव राज शास्त्र), पी एच डी घटयक्ष, राजनीति शास्त्र विभाग एस आर के महाविद्यालय, फीरोजाबाद (उ प्र) मूल्य पच्चीस रुपये

की

पुण्य स्मृति मे

सादर समर्पित

परम पूज्य पिताजी

स्वर्गीय



प्राक्कथन

प्रस्तुत पुस्तक एम ए कदााया के विद्यापिया के लिए विभिन्न विस्वविद्यालया में पाठ्यत्रम को ध्यान में रसकर निसी गयी है। हिसी में आधुनिक सासन ध्यवस्या पर अनेन पुत्ताक उपलब्ध हैं निष्ठ यह पुत्ताक उस यम में सवधा एक नवीन प्रयास है। सेवन ने शासन एवं उसके विजित्त अगा के सेंब्रान्तिक पक्त का उल्लेख करते हुए यह प्रयास किया है कि विद्यार्थी शासनन्त न के विभिन्न पहलुओ एव समस्याभा ना भाग प्राप्त करे और स्वय म स्वतात्र चितन की क्षमता विकासित करें। लेखन निसी मोलिनता ना हाया नहीं करता, निष्ठ विषय नो यथासाध्य स्पष्ट करने एव नमबद्ध रूप म प्रस्तुत करने का पूर्ण प्रयत्न किया गया है। स्थान स्थान पर जुलनात्मव अध्ययन भी दिये गय हैं। मापा सरल एव सुवीध है।

पुस्तक की रचना में लेखक ने जिन प्रस्थात विद्वानों की रचनाआ एव पुस्तको का सहारा विया है, उनके प्रति वह हृदय से आमारी है। इसके अतिरिक्त लेखक गुरु वर पूज्य हो सत्यनारायण हुने (प्राचाय, आगरा कालेज) तथा हो इकवाल नारायन (विमागाध्यक्ष, राजनीति साहत्र, राजस्थान विस्वविद्यालय), हो रामप्रकास पाण्डे (प्राचाय, चातकीय महाविचालय, नरसिंहपुर, म प्र), प्रो महेसदत्त मिस्र (अध्यक्ष, रीजनीति शास्त्र, जनलपुर विस्वतिशालय), हाँ टी जी दुगवेकर (राजनीति शास्त्र बिमाग, जवलपुर विस्वविद्यालय), हाँ श्रीराम महेन्वरी (विमागान्यस, लोक प्रशासन, मारतीय लोक प्रवासन संस्थान, नई दिल्ली), श्री रामच इ धर्मा (नारायण महाविद्यालय, विकोहाबाद) एव प्राचाय श्री असरनाय क्षमां का उनके निर तर प्रोत्साहन एव सहयोग के तिए अत्य त आमारी है। अपने महानिवालय के भूतपुत्र प्राचाय एव नितमान सह-सन्ति भी हरणासहाय गग का भी में विशेष रूप से म्हणी एवं जामारी हैं, जी प्रारम्भ से ही प्रणान्त्रीत रहें और जिहोंने प्रत्येत पग पर पुस्तक सेखन में गेरा मागदशन किया। विमागीय सहयोगी हाँ टी के बद्धवाल एव श्री लोम पाल सिंह जी ने भी समय समय पर अनेक जपयोगी सुकाब देकर मेरी विश्लेष सहायवा की है। मैं जनका भी कामारी हूँ। अत में, मैं अपनी उनी थीमती बैदेही विभीतिया (प्रवक्ता, नी ही एम बिग्री कालेज, तिकोहाबाद) एव वपन पुत्र चि अजिनकुमार को जनके सहयोग के लिए मुमाशीय देता हूं। उनके सहयोग के अमाव म में सम्मवत पुस्तक लिख ही न पाता ।

मै अपने प्रकाशक श्री प्रकाशनारायण जी का भी आमारी हूँ जि होने बढ़े धय के साथ अत्यात आकर्षित साज सज्जा मे पुस्तक का प्रकाशन किया और मुद्रण के बीच

आने वाली फठिनाइयो ने बावजूद भी मुक्ते निरत्तर प्रोत्साहित करते रहे।

यदि विद्यार्थी समुदाय इस पुस्तक से लामाचित होता है, तो मैं अपने परिश्रम

को सफल मानुगा। पुस्तक को अधिक उपयोगी बनाने हेतु सुकाव सादर आमित हैं।

कार्तिक पूर्णिमा 18-11-1975 भद्रदत्तः गर्मा

विषय-सूची

घटयाय	ग्यथय-सूः	वी	
1 राज्य एव शासन [राज्य एव शासन राज्य एव शासन] 2 राज्यों क	समाज -	विधान	9
2 राज्यो एव सविधाः विगीकरण का आधु आधुनिक युग के व्या	नो का वर्गोकरण गर, विभिन्न योजनाएँ—अ करण, लोकत म्	ाय, राज्य एव राष्ट्र,	1
अधुनिक युग के वर्ग अधुनिक युग के वर्ग सबिधान पिरमापा, आवश्यक वर्गीकरण, लिक्सिक	करण, लोकत त्र] ता, बाद्या म	रस्त्र ना वर्गीकरण,	13
डुप्परिवर्तनीय सविधान में संशोधन, विमिन्न सर्वि संयुक्त राज्य	ता, बादरा सविधान के संस विधान एवं उनका विकास, उण-दोप, सविधान का ह विधान को कोधान का हिंद्यान की कोधान प्रणालि	ण, सविधाना का सुपरिवतनीय एव	42
4 सविधानवाद [सूमिका, प्राचीन सकि	^{स्वट} जरलैण्ड, सोवियत रूस, : रम्पराएँ एवं अभिसमय]	गौ—प्रेट ब्रिटेन, नारत, यायिक	
ि देववकर्षा का कि	(स्मराएँ एवं अभिसमय) वाद, मध्य पुग में सविधानवा फेंच शातियों तथा उनका में सविधानवाद का लोकत व	प्रकाशिक	
ाक पुष्यकरण का विद्यात ति सुक्त राज्य कोरिक राज्य कोरिका म अवरोध एव का तिद्या त—पेट ब्रिटेन, फास,	ं विश्वासा) हिंद्य शक्तियों का पृथकरण संजुलन, अय देशा में शक्ति है सोवियत हिंस, भारत, निष्कप	ा, संयुक्त पनकरण 	

5

ग्रध्याय

б एकात्मक एव संघात्मक राज्य

[शक्तियों का विमाजन, एकात्मक शासन गुण-दोष, संघात्मक शासन गुण दोष, संघवाद का इतिहास, संघ शासन के निर्माण में सहायक तत्व, परिसपी

1 सघवाद का व्यावहारिक स्वरूप

[संयुक्त राज्य बमेरिका की संघीय व्यवस्था, आस्ट्रेलिया की संघीय व्यवस्था, कनाडा का संघ, स्विस परिसंध, सोविवत रूस एव संघवाद, जर्मनी में संघवाद, पाकिस्तान एवं संघवाद, यूगोस्लाविया की संघीय व्यवस्था, भारतीय संघीय व्यवस्था, मलेशिया एवं संघवाद, नाइ जीरिया, संघवाद की आधुनिक प्रवृत्तिया]

व्यवस्थापिका

8 व्यवस्थाविका

[भूमिका व्यवस्थापिका का विकास, प्रकार, काय, आकार, कार्यकाल, विघटन एव उप चुनाव, व्यवस्थापिका को प्रमावित करना]

2

2.

30

विसदनवाद

[भूमिना, द्विसदनवाद, एकसदनवाद, क्या द्वितीय सदत आवश्यक है ?, उच्च सदनो का सगठन, वर्गीकरण]

10 व्यवस्थापिका-उच्च सदन

[इगर्लण्ड की लॉट समा, मयुक्त गुज्य अमेरिका वा द्वितीय (उच्च) सदन—सीनेट, प्राप्त का द्वितीय सदन—सीनेट, आस्ट्रेलिया का दितीय सदन—सीनेट, सोवियत रूस का द्वितीय सदन—राष्ट्रजातीय सीवियत मारतीय गणराज्य वा द्वितीय सदन—राज्यसमा, नार्वे का द्वितीय सदन, आयर गणराज्य वा द्वितीय सदन, प्रगोस्लाविया का द्वितीय सदन, प्रगोस्लाविया का द्वितीय सदन,

व्यवस्थापिका—प्रयम या निम्न सदन

प्रिमिना, विदेश का निम्म सदन—कोम स समा, अमेरिकी प्रतिनिधि सदन, इस की सुप्रीम सीविवत का निम्म सदन—सप सोविवत, काराडा की कोम स समा, आरट्रेसिया का प्रतिनिधि सदन, स्विद्वर नाडा की कोम स समा, आरट्रेसिया का प्रतिनिधि सदन, स्विद्वर राष्ट्र का प्रथम सदन—राष्ट्रीय परियर, साम्मवादी चीन की व्यवस्था पिका—राष्ट्रीय वत्रवादी कोचेल, क्षेत्र गणराज्य के निम्म सदन, जापान की डाइट (व्यवस्थापिका), नेपाल की स्वाहर व्यवस्थापिका, स्वाहर स्वाह

114		पृष्ठ
	च्यवस्थापिका—िविध निर्माण प्रक्रिया एव सम्बन्धित विषय [ध्यवस्थापिका के अध्यक्ष उच्च सदनी के अध्यक्ष, निर्दिश कॉम स समा का अध्यक्ष, अमेरिकी प्रतिनिधि सदन का अध्यक्ष, फास मे अध्यक्ष ना पद, गारतीय लोकसमा का स्पीकर या अध्यक्ष, विधि निर्माण प्रक्रिया—प्रेट ब्रिटेन, सबुक्त राज्य अमेरिका, भारत की गैर-विसीय	355
	एय वित्तीय विधि निर्माण प्रित्रया]	
}	विधायो समिति-ध्यवस्था [भूमिका, ग्रेट त्रिटेन की समिति व्यवस्था, संयुक्त राज्य अमेरिका की समिति व्यवस्था, फास में ममिति व्यवस्था, सोवियन रूम में समिति व्यवस्था, भारत से समिति व्यवस्था]	402
4	प्रदत्त विधान	435
	[भूमिका, प्रवत्त विधान का विकास, विभिन्न देशो स प्रदत्त विधान प्रेट ब्रिटेन, फास, समुक्त राज्य अमेरिका, भारत, आलोचना, उपयोगिना]	
5	प्रत्यक्ष विधि निर्माण	451
ŧ	[भूमिका, जनमत सम्रह, अभिक्रम, प्रत्यावतन, स्विट्जरलैण्ड मे जन- मत-सम्रह एव अभिक्रम, ममीला]	
6	ससदीय विशेषाधिकार	461
	[अय, प्रेट ब्रिटेन मे समदीय विज्ञेयाधिकार, मान्त मे ससदीय विज्ञेयाधिकार, अय देशा में विज्ञेयाधिकार]	
	कायपालिका	
17	कायपासिका [अय एव प्रश्नृति, प्रवार, वशानुगत एव निर्वाचित वायपासिका, नाममाप्र एव नास्त्रविव कायपासिका, ससदीय एव अवसदीय कार्य- पासिका, कार्यभासिका को अवधि, शक्तियों एव काय, ससदीय कार्य- पासिका, कार्यक्षास्मक कार्यपासिका	474
18	बिटिश सत्तरीय अपवा माँ प्रमण्डलीय क्षार्यपालिका [मूमिना, अप, विकास, विशेषताएँ, मिंत्रमण्डल एव माँ व परिषद, पाम, संगठन, मिंत्रमण्डलीय उत्तरदायिल, मित्रमण्डल का अधि नायक्रव, ब्रिटिश प्रधानमात्री, शक्तियों, प्रधानमात्री की स्थिति]	495
19	फांस, जर्मनी एव सोवियत रस की कायपासिका [फासीसी कायपासिका, फासीसी मित्रमण्डल, चतुष फेंच गणराज्य, मास मे सामूहिक उत्तरदायित्व, फेंच प्रधानमात्री, फेंच गणराज्य का राष्ट्र-	529

<i>घ्रध्याय</i>	पृष्ठ
पित, फास के गणराज्य (1958) का राष्ट्रपति, मिनमण्डल, जमन कायपालिका—बीमर सिवधान के अतर्गत कायपालिका, तीसरे रीक का शासन, द्वितीय विक्वयुद्ध के बाद जमन शासन, सोवियत काय- पालिका, मित्रमण्डल, सोवियत सघ की सर्वोज्ज्व सोवियत की प्रेसीडियम, शक्तिया, अध्यक्ष, प्रेसीडियम की यदाण दिवति।	
20 कुछ अप देशो की कार्यपालिकाएँ	571
[जापान, साम्यवादी चीन, क्लाडा, आयर गणराज्य, आस्ट्रेलिया, यूगी- स्लाविया, नेपाल, पाकिस्तान की कायपालिकाएँ]	
21 भारतीय ससदीय कार्यपालिका	608
[राष्ट्रपति निर्वाचन, शक्तियाँ, स्थिति, भारतीय के द्रीय मिनमण्डल काय एव धक्तिया, मिनमण्डलीय उत्तरदायित्व, समीक्षा, भारतीय प्रधानमंत्री नियुक्ति, काय एव दायित्व, स्थिति, भारतीय सध मे राज्यपात चक्तिया, स्थिति, साराक्ष, राज्य मिनमण्डल, मुख्यमंत्री] 22 सपुक्त राज्य अमेरिका को कार्यपालका—राष्ट्रपति हिंचांचन, कार्यक्ष एव राष्ट्रपति, राष्ट्रपति निर्वाचन, क्रिया एव अधिकार, कार्यक्ष एव राष्ट्रपति, राष्ट्रपति वल के नेता ने रूप मे, मुख्याकन, राष्ट्रपति एव उत्तवा मिनमण्डल, राष्ट्रपति एव व्रिटिश राजा, राष्ट्रपति एव व्रिटिश	649
प्रधानम त्री]	
23 हिबस समीय कायपालिका [समीय परिषद, शक्तियाँ, परिसम्ब का अध्यक्ष, समीय परिषद एव समीय समा, समीय परिषद से ससदीय एव अध्यक्षात्मक तत्वो का मित्रण]	675
24 कोक-सेबा [परिमापा, नाय, मुख्य विद्योपताएँ, इतिहास, प्रविक्षण, मित्रयो एव लोन सेवा ने सम्बण, लोक सवा से सम्बण्यत अप्य थातॅ, पदो नित, लोक-सेवा म भ्रष्टाचार, लोन सेवा एव राजनीति, समीक्षा]	683
न्यायपा लिका	

[भूमिना, यायपालिना का विकास, काय, सगठन, यायाधीशो की नियुक्ति, यायपालिका की स्वतात्रता, कायकाल अवकाण प्रहण करने

25

ग्यायपालिका

मी आयु]

732

		•
26	विधि का शासन एव प्रशासकीय विधि	746
	[विधि का शासन गुण-दोष, प्रशासकीय विधि, सिद्धात, विधि का	
	शासन बनाम प्रशासकीय विधि, समीक्षा]	
27	कुछ प्रमुख देशो की न्यायपालिकाएँ	768
	[ग्रेट ब्रिटेन की याय व्यवस्था, स्विस यायपालिका, कनाडा की याय	
	पालिका, आस्ट्रेलिया की यायपालिका, आयरलैण्ड की यायपालिका,	
	जापान की यायपालिका, फास की याय ध्यवस्था, नेपाल की याय-	
	पालिका, पाकिस्तान की न्यायपालिका, सोवियत 'यायपालिका, साम्य-	
	वादी चीन मे 'यायपालिका, यूगोस्लाविया की 'याय व्यवस्था]	
28	सयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायपालिका	824
	भूमिका, सगठन, सर्वोच्च यायालय का सगठन क्षेत्राधिकार,	
	अमेरिनी सर्वाच्च "यायालय एव न्यायिक पुनरीक्षण, सर्वोच्च "यायालय	
	एव मौलिक अधिकार, महत्व, सर्वोच्च "यायालय के सुधार के प्रयत्न]	
29	भारतीय ऱ्यायपालिका	841
	[भारतीय सर्वोच्च यायालय क्षेत्राधिकार एव शक्तिया, सर्वोच्च	
	यायालय एव मौलिक अधिकार, मारतीय सर्वोच्च यायालय एव	
	'यायिक पुनरीक्षण, भारत मे 'यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र, मूल्या-	
	कन, यायाधीको की स्थत त्रता]	
	लोकतान्त्रिक सस्थाएँ	
30	निर्वाचन एव प्रतिनिधिस्व	856
	[भूमिका, मताधिकार, सावभौम मताधिकार, निर्वाचन, गुप्त एव	
	सावजितक मतदान, निर्वाचन-क्षेत्रा का निर्माण, एकसदस्यी एव बहु-	
	सदस्यी निर्वाचन क्षेत्र, अल्पसब्यको को प्रतिनिधित्व, समानुपातिक	
	प्रतिनिधिरव प्रणाली, सीमित मत प्रणाली, सामूहिक मत प्रणाली, एकल	
	असक्रमणीय मत प्रणाली, साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व, निर्वाचन की आय	
	पद्धतिया, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व]	
31	लोकमत	886
	[अय, निर्माण एव प्रसार के साधन, स्वस्य लोव मत वे निर्माण के	
20	लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, भारत मे लोकमत]	898
32	दबाव-समूह [अथ, दबाव-समूह वे निर तर बढते हुए महस्व के लिए उत्तरदायी	070
	त्तरव, दबाव समूहों के काय एवं पद्धति, विभिन्न देशों में दबाव-समूहों	
	mil and a was the transfer of the a sale as a sale as Alle	

अ ०५।	14	पू
	की स्थिति, संयुक्त राज्य बमेरिका में दबाव समूह, ग्रेट ब्रिटेन में दब	ia-
	समूह, फास में दबाव समूह, जापान में दबाव समूह, मारत में दबा	a -
	समूह, निष्कष]	
33	मौलिक अधिकार	92
	[भूमिका, प्रकार, क्या मौलिक अधिवारो का सविधान में उल्लेख हो	ना
	चाहिए ?, विभिन्न देशा मे मौलिक अधिकार एव नागरिक स्वतः	ৰ-
	ताएँग्रेट ब्रिटेन, सयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैण्ड, फास, सी	ब-
	यत रूस, चीन, यूगोस्लाविया मे मौलिक अधिकार]	
34	भारत मे मौलिक अधिकार	94:
	[भूमिका, अथ, समानता का अधिकार, स्वतात्रता का अधिकार	τ,
	वैयक्तिक स्वत त्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वत नता क	7
	अधिकार, सास्कृतिक और शिक्षा सम्ब घी अधिकार, सम्पत्ति का अधि	
	कार, सवैधानिक उपचारो का अधिकार, समीक्षा, मौलिक अधिका	र
	बनाम नीति निर्देशक तत्व]	
35	स्थानीय शासन	968
	[भूमिना, महत्व, काय एव स्रोत, ग्रेट ब्रिटेन कास, सयुक्त राज्य	
	अमेरिका, भारत में स्थानीय शासन, सोवियत रूस में स्थानीय शासन	
	साम्यवादी चीन में स्थानीय शासन, पानिस्तान में बुनियादी लोनत में	
36	राजनीतिक दल द्विदलीय एव एकदलीय पढित	1002
	[भूमिना परिमापा, महत्व, दोप, दल विहीन सोनतात्र, दलों ने	
	प्रकार द्विदलीय पद्धति ग्रेट त्रिटेन की दलीय पद्धति, संयुक्त राज्य	
	अमेरिना नी दलीय व्यवस्था, एनदलीय व्यवस्था, एनदलीय पदित ना उदय एव विनास, सोवियत रूस ना साम्यवादी दल, चीन ना	
	साम्यवादी दल, यूगोस्लाविया में दलीय ध्यवस्था]	
37	राजनीतिक दस बहुदलीय प्रद्वति	1045
31	भूमिना, फ्रांस नी दलीय व्यवस्था, मारतीय दलीय व्यवस्था, पानि-	
	स्तान की दलीय व्यवस्था, जापान मे दलीय पद्धति]	
परित		
1	भारत म सर्वैपानिक सशोधन	1073
2	मेशवानन्द भारती विवाद	1075

राज्य एव शासन [STATE AND GOVERNMENT]

'राज्य' नामक सामाजिक सगठन राजनीतिशास्त्र के अध्ययन का प्रधान विषय है।¹ गानर के अनुसार "सक्षेप म राजनीतिशास्त्र राज्य से प्रारम्म होता है और राज्य म ही उसकी परिसमाप्ति होती है।" राजनीतिशास्त्र की परिमापा विभिन्त विद्वानी ने भिन भिन इंटिटनोणा से की है। सामायत चार इंटिटकोण है। प्रथम इंटिटनोण के ममथको ने परिभाषा मे राज्य को ही अधिक महत्व दिया है। यानर के अतिरिक्त स्लटक्ली (Bluntschlt) एव गेराइस (Gareis) आदि विद्वान इस श्रेणी मे आते हैं। सीले (Seelev) की परिमापा म शासन पर बल दिया गया है। ततीय हुन्टिकोण का प्रतिनिधित्व गिलकाइस्ट करता है। उसके अनुसार ''राजनीतिशास्त्र के अत्तगत राज्यतथा सरकार का अध्ययन किया जाता है।" फेंच विद्वान पॉल जाने (Paul Janet) के अनु सार राजनीतिशास्त्र राज्य के आधारो तथा शासन के सिद्धा तो की समीक्षा करता है। गैटिल चतुथ इध्टिकोण नो अभिव्यक्त करता है "राजनीतिशास्य के अध्ययन के मुग्य विषय राज्य, सरकार तथा विधि है।" उपर्यक्त इष्टिकोणो मे गेटिल की परिभापा अधिक ग्राह्म है। राज्य और सरकार का एक दूसरे से अभिन सम्बन्ध है। सरकार के बिना राज्य का कोई अथ हो ही नहीं सकता। सच तो यह है कि 'राज्य' शब्द मे सरकार का माव निहित है। अत राजनीतिशास्त्र के अतागत राज्य व सरकार दीनो का अध्ययन सम्मिलित है। राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति एव किया वयन विधि द्वारा ही सम्मव है। उपयक्त सभी परिमापाओं म राज्य नाम की सस्या को अधिक महत्व दिया गया है तथा मनुष्यो की अपेक्षा राजनीतिशास्त्र समाज मे मानवीय आचरण के नैतिक प्रश्न से सम्बिधित है। राज्य क्या है ?, हम उसकी आज्ञा क्यो मानते हैं एवं हम क्य उसकी आज्ञा मानने से इकार कर सकते हैं ?, राज्य की सत्ता एव व्यक्तिकी स्वतात्रता मे समावय कैसे स्थापित किया जाये ?, आदि प्रश्न राजनीतिशास्त्र

^{1 &#}x27;Political Science may be defined as the science of State'—Gettell, R G Political Science 1956 (Indian edn.) p 3

^{2 &}quot;In short Political Science begins and ends with 'the 'State — Garner, J W Political Science and Governments, 1951 (Indian edn), p 8

Political Science deals with State and Government '—Gilchrist R N Principles of Political Science, 1930, p. 1

⁴ Political Science is mainly interested in "State, Government and Law" —Gettell Political Science, 1956, pp 3 4

के शास्वत प्रश्न हैं, जिनके विभिन्न कालों में भिन भिन विद्वानों ने भिन्न भिन्न उत्तर दिये हैं। राजनीतिक जीवन के उद्देश्य जीवन-उद्देश्यों से भिन्न नहीं होते, अंत राज्य से सम्बचित उपर्युक्त प्रश्नो के उत्तर हमारी औचित्य एव अनौवित्य की धारणा पर निभर करते हैं।

राज्य यूनानियों के लिए एक नितक अवयवी या क्योंकि राज्य की सदस्यता से ही सदगुणी जीवन की प्राप्ति सम्मव थी। राज्य को अवयवी मानने का अथ है कि व्यक्ति राज्य के अग हैं। लेकिन यूनानिया ने राज्य को साधन माना था। प्रत्ययवादियो (Idealists) की हृष्टि मे भी राज्य नैतिक सस्या है । हेगेल (Hegel) जैसे प्रत्ययवादिया के लिए राज्य 'भूतल पर ईश्वरीय यात्रा' एव नैतिकता का मूर्तिमान रूप है। उदार प्रत्ययवादी ग्रीन (Green) उसे साध्य न मानकर साधन मानता है—लेकिन, फिर मी, राज्य नैतिक सस्या है। राज्य को नैतिक महत्व देने वाले विचारक उसे अवयवी एव विकासवादी मानते हैं। इसके विपरीत, कुछ विचारक राज्य की यात्र (machine) मानते हैं जो मनुष्यो द्वारा निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्मित किया गया है। उनके अनुसार व्यक्ति सत्य (real) है जबकि राज्य व्यक्तियों के द्वारा निर्मित है अत कृतिम (artificial) है एव राज्य केवल साधन मात्र है। यूनानियो की राज्य की अवसवी भारणा को स्टाईकवादियो द्वारा सम्पूण मानवता के सादम मे प्रयोग किया गया था। मध्य-युग मे ईसाई विचारको मे भी अवयवी धारणा का प्राधाय रहा। 17वी सदी के प्रारम्म मे यात्रिक घारणा का प्रमाव वडा । हाँबस (Hobbes) एव लॉक (Locke) इसके प्रतिनिधि विचारक हैं। पर तु इसी (Rousseau) एव प्रत्ययवादियो (Idealists) ने इस धारणा को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद याजिक धारणा पुन बलवती हो गयी थी। राज्य के स्वरूप की एक अप धारणा ऐतिहासिक सम्बद्धता या अनुरूपता (historical coherence) की परम्परा है। इस घारणा के समयक ऐतिहासिक विकास पर यल देते हैं तथा निरपेक्ष मापदण्डो को अस्वीकार करते हैं । वे राज्य को प्राष्ट्रतिक जगत की नकल नही मानते। लेकिन एक सीमा तक राज्य की प्राष्ट्रतिक माना जा सकता है बयोक्ति यह ऐतिहासिक विकास का परिणाम है जो स्वय प्रकृति का अग है। साथ ही एक सीमा तक यह अतिम सी है क्योंकि यह ऐसे मतुष्यों का परिणाम है जो प्रकृति या अनुगमन नही करते अपितु उसे परिवर्तित करते हैं। राज्य के अवयवी विचारक विवनवादी थे। यात्रिन विचारन इच्छा (will) नो प्रधानता देते थे। राज्य अवयवी विचारको वे लिए स्वामाविक या प्राकृतिक (natural) है तो यात्रिक विचारका के तिए वृत्रिम । राजनीतिनास्त्र ने सभी निचारनो ने समाज म नतिर जीवन ना दायिहर राज्य को सौंपा है। राज्य एक धारणा है। शासन वह यात्र है जिससे राज्य के उद्देश्यो को प्राप्त किया जाना है। बत राज्य के अध्ययन में शासन का विश्लेषण एवं उसकी

The state is 'march of God on Earth —Hegel Wayper C L Politi al Thought (1954) Introduction p x1

काय-पदित का अध्ययन निहित है। शासन का स्वरूप एवं कार्य-पदित हर युग में एक्सी नहीं रही है। समय-समय पर उनमें परिवतन होते रहे हैं। प्राचीन यूनान और रोम में सबसे पहले राजतात्र या, उसके बाद कुसीनतात्र एवं बात में प्रजातात्र की स्थापना हुई थी। आधुनिक अगत में शासन के विभिन्न स्वरूप हैं।

सामाय बोलचाल की भाषा में राज्य, राष्ट्र, समाज एव शासन का प्रयोग समानार्थी झब्दों के रूप में किया जाता है। परतु इन शब्दों में महत्वपूण अत्तर है। अत इनवा विक्लेषण अपक्षित है।

राज्य (STATE)

सभी सामाजिक सस्याओं में राज्य सबसे अधिक शांकिशाली एव शांक्तत सस्या है। जहां मनुष्य रहते हैं वहां संगठन एवं सत्ता स्वामाविक है तथा जहां सत्ता एवं सनुष्य रहते हैं वहां संगठन एवं सत्ता स्वामाविक है तथा जहां सत्ता एवं समृद्धि ने लिए आवश्यक है। यूनानी विचारक इसे प्राकृतिक एवं आवश्यक (natural and necessary) सत्या मानते थे। अरस्तू (Aristotle) के अनुतार राज्य का उदय व्यवस्या एवं शांति ने लिए हुआ था परन्तु सवजीवन की प्राप्ति ने लिए वह नायम है। राज्य सम्यता का सुजनकर्ता है। सामाजिक सहयोग एवं सामृहिक प्यस्त विज्ञास की एक अवस्था में राज्य के रूप में अभिक्यक्त होते है। राज्य स्वमाविक, अविनया एवं शक्तिशाली तथा शांवित सस्या है। इस अथ में यह अप्य अनेक मानवीय समुदायों से मिन है।

राज्य नी विभिन्न परिमापाएँ दी गयी है। प्रत्येन विद्वान राज्य को एक विशिष्ट हिंदिकोण से वेनता है एव उसी के अनुसार उसनी परिमापा करता है। यूनानी विचारक अरस्तु के अनुसार "राज्य कुना एव सामा के उस समुदाय का नाम है जिसका उद्देश्य पूण एव स्वावलस्वी अर्थात सुखी एव सम्मानयुक्त जीवन की प्राप्ति हो।" सिसेरो (Cicero), जी बोदा (Jean Bodin) एव गीशियस (Grotius) ने भी राज्य ने परिमापाएँ दी हैं पर तु वे आधुनिक समाज पर लागू नहीं होती। हॉलण्ड ने अपनी परिमापाएँ दी हैं पर तु वे आधुनिक समाज पर लागू नहीं होती। हॉलण्ड ने अपनी परिमापा में प्रभुत्व के तरव को स्थान नहीं दिया है। उसके अनुसार "राज्य ऐसे मनुष्यो ना बहुसख्यक समूह है जो साधारणत्या किसी निव्चित भू-माग पर निवास करता हो और जिनसे बहुसत्या नी अपक्षा किसी निव्चित वम ने सीपो की च्छा उस बहुसख्या तथा वात्र को चािक ने वारण उन सब पर चलती हो जो उसका विरोध करते हो।"" इस परिमापा म एन दोग यह है कि राज्य वो समुह माना गया है।

⁷ The State ' m a numerous assemblage of human beings, generally occupying a certain territory, among whom the will of the majority or of an ascertainable class of persons m by the strength of such a majority or class made to prevail against any of their num ber who oppose it "—Holland Sir TE. The Elements of Jurispin dence 13th edn p 46 quoted by M P Tandon Public International Law, 1971 p 80

फिलिमोर (Phillimore) ने अ तराष्ट्रीय विधि नी हिन्ट से परिभाषा नी है। डॉ बुडरो विलसन के अनुसार एक निश्चित भू माग पर विधि के लिए संगठिन जनता राज्य है। वर्गेस ने अनुसार राज्य ''एक इनाई के रूप मे सगठित मनुष्य जाति वा एक विशिष्ट भाग है।" इसी से मिलती जुलती परिभाषा ब्लुटश्ली की है। उनके अपूमार एक निश्चित क्षेत्र के राजनीतिक रूप में संगठित व्यक्ति राज्य हैं। 10 सबसे अधिक वैज्ञानिक परिमापाएँ गानर और गेटिल की प्रतीत होती हैं। डॉ गानर के अनसार 'राज्य मनुष्यो के उस समुदाय का नाम है जो किसी निश्चित क्षत्र पर स्थायी रूप से निवास करता हो, जो बाह्य नियात्रण से स्वतात अथवा लगमग स्वतात हो, जिसकी एसी सुगठित सरकार हो जिसके आदेशों का उसके बहसख्यक निवासी आदतवश पालन करते हो । 11 गानर की इस परिमापा में चारो तस्वी-भूमि, जनता, शासन एव प्रभुत्व- का उल्लेख है । डॉ आशीर्वाहम ने मकाइवर की राज्य की निम्न परिभाषा को सबश्रेप्ठ माना है क्योंकि उक्त परिमापा में विधि, शासन, दमनकारी शक्ति (coercive power), सामाजिक एकता, स्पष्ट मु खण्ड एव नामाजिक व्यवस्था के हेतु शास्त्रत बाह्य स्थिति का उल्लेख किया गया है। 12 डॉ आशीर्वादम् इन तत्वो को श्रेष्ठ एव राज्य के लिए आवश्यक मानते है। भैकाइवर के अनुसार "राज्य शासन द्वारा विज्ञापित विधि ने अधीन काय करने वाला समुदाय है जो (शासन) दमनकारी शक्ति के माध्यम से स्पष्टत अकित भू खण्ड पर वसने वासे समाज मे सामाजिक व्यवस्था की शाश्वत बाह्य स्थित कायम रखता है।"" मैकाइवर की इस परिमापा मे बहुलवाद का गुण है। लास्की (Laski) के अनुसार ' राज्य वह प्रादेशिक समाज है जो सरकार एव शासितों मे विभक्त हो और जो अपने सौगोलिक क्षेत्र के भीतर अन्य सभी सस्याओं पर सर्वाच्चता

The State ' is a people organized for law within a definite territory' —Woodrow Wilson quoted by Asirvatham, p 26

⁹ The State "is a particular portion of mankind viewed as an or ganized unit —Burgess, quoted by Garner op ctt, p 48

"The State with polytically corrected people of a definite territ

^{10 &}quot;The State m the politically organized people of a definite territory —Bluntschli quoted by Garner op cit, p 48

¹¹ The State is a community of persons more or less numerous permanently occupying a definite portion of territory, independent or nearly so of external control and possessing an organized government to which the great body of inhabitants render habitual obedience "—Garner Political Science and Government, 1951, p. 49

¹² Asirvatham E Political Theory 1965, p 26

¹³ The State is an association which, acting through law as promulgated by a government endowed to this end with coorcive power, maintains within a community territorially demarcated, the universal external conditions of social order '—MacIver, quoted by Asirvatham Political Theory 1965 p 26

का द्वारा करता हो ।"¹⁸ यह परिमापा विश्वद न होते हुए मी स्पप्ट व सही है। गैटिल के अनुसार "राज्य व्यक्तियों का वह समुदाय है जो स्थायी रूप से निश्चित भूभाग पर दसा हुआ हो, विजिक दृष्टि से बाह्य नियत्रण से मुक्त हो और जिसकी सगठित सरकार हो, जो उसके क्षेत्राधिकार के अंतगत निवास करने वाले सभी व्यक्तियों एवं समूहों के लिए कानून बनाती हो और लागू करती हो।"¹⁵

श्रत आधुनिक राज्य एक राजनीतिक सगठन है जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के ऊपर निवानण रखता है तथा व्यवस्था एव शानित स्थापित करके उन वाहा परिस्थितियों का निर्माण करता है जो मनुष्या के सर्वागीण विकास के लिए आवस्थक हैं। राज्य के चार अनिवाय तत्व हैं—भूमि, जनसरया, सरकार एवं प्रभरत।

বাড়য ব समाज (STATE AND SOCIETY)

राज्य व समाज एक नहीं हैं। दोनों में अत्तर हैं। बाकर के अनुसार समाज से तारपय उन विभिन्न उद्देश्या एव सस्याओं वाले ऐ ज्विक निकायों और समुदायों के योग से हैं जो राष्ट्र के अतुतार देखने को मिलते हैं (बिरिक जो उन सम्बाधा ने कारण राष्ट्र के बाहर भी फैल जाते हैं जि है वे अप राष्ट्रों में स्थित सस्याओं के साथ स्थान्त करते हैं)। सामूहिक इष्टि से तथा समाज के रूप में ये कब समुदाय सामाजिक तत्व का निमर्ण करते हैं जो सामा य एव व्यापक अथ से समाज कहलाता है। 18 अत परिवार, जाति, धामिक, राजनीतिक एव आधिक सम्बाध, विभिन्न रीति रिवाजों, इदियों, परस्पराओं आदि के जिटल सम्बाधों का नाम ही समाज है। प्राचीन यूनानियों के लिए समाज ही राज्य वा । पराचु आज यह सत्य नहीं है। राज्य केवल राजनीतिक सगठन है जविक समाज राजनीति के प्रत्येक क्षेत्र पर नियानण स्थापित करता है। प्रत्ययवादी विचारक होंगा एव हिटलर, मुझोलिनी आदि कारीवादी नेताआ का गहीं हिटकोंण था। इनकी इष्टि में राज्य सर्वोपिर था तथा जीवन का कोई पहलू ऐसा नहीं था जो राज्य के काशुत्र से साहर हो। सोवियत रूस का राज्य भी समग्रवादी है किकन यहा राज्य का समाज में भद है। सम्यता के विकास के साथ सामाजिक जीवन में राज्य का महत्व बदाता जा रहा है।

¹⁴ The State 'm a territorial society divided into government and subjects claiming, within its allotted physical area, supremacy over all other institutions "—Laski A Grammar of Politics 1941, p. 21

¹⁵ A State is "a community of persons permanently occupying a definite territory, legally independent of external control and possessing an organized government which creates and administers law over all persons and groups within its jurisdiction"— Gettell Political Science, 1956 (Indian edn.), p. 20

¹⁶ Barker, E Principles of Social and Political Theory, 1956, p 3

राज्य एव अन्य समुदाय (STATE AND OTHER ASSOCIATIONS)

राज्य भी एक समुदाय है पर तु अय समुदायों से भिन है। मकाइयर के अनुसार समुदाय से अथ सामाय जहेंस्य की प्राप्ति के लिए परस्पर सम्द्रद एवं समिठत सदस्यों के समुह से हैं। 12 समुदाय की परिभाषा में समुदाय के सदस्यों के सामाय उद्देश्य एवं समान बाग प्रणाली पर वल दिया गया है। समुदाय मनुष्या के लिए आव स्थम है। हर व्यक्ति की अनेन आवस्यकताएँ, हित क्षिया, आदण एवं लक्ष्य होते हैं। अठ इनकी पूर्ति के लिए समान उद्देश्यों में विश्वास करने वाले व्यक्तियों द्वारा मिनकर काय करना स्वामाविक है। फलत समुदायों ना जाम होता है। समाज में नाना प्रकार के समुदाय पाये जाते हैं। बहुलवादी विचारक राज्य को मनुष्या का नहीं अपितु समु-वायों का समुदाय मानते हैं। लेकिन राज्य अय समुदायों की भाति समुदाय नहीं है। उनमें निम्म अतर हैं

(अ) राज्य की माति समुदाया के निश्चित भू माग नहीं होते।

(क्षा) समुदायों नी सदस्यता ऐच्छिक और राज्य नी अनिवास है। एन व्यक्ति एक समुदाय की सदस्यता त्यागकर दूसरे की प्रहण कर सकता है परंतु राज्य नी सदस्यता स्वेच्छापुवन प्रहण या त्यागी नहीं जा सकती।

(इ) राज्य के उद्देश्य समुदाय की तुलना में व्यापक होते हैं।

(ई) समुदाय राज्य की माति प्रभुत्व से युक्त नहीं होता । समुदायों का अस्तित्व राज्य की इच्छा पर निमर होता है। राज्य समुदायों को सरक्षण देता है तया अवाछनीय समुदाया को मग कर अवध घोषित कर सकता है।

(उ) राज्य समुदाय की तुलना में अधिक स्यायी है। समाज स्वामाविक स्पायी है। समाज स्वामाविक सस्या है और राज्य से पहले का है। समाज में मनुष्य लगम लेता है, उसी में बढता है तथा वही उसका लालन-पालन होता है।

समाज ना आधार नैतिन वल है जबिन राज्य ना आधार शक्ति है। **धाकर** के अनुसार "समाज ना क्षेत्र ऐन्छिन सहयोग है, उसकी शक्ति सदिन्छा है एवं पढित नमनीय है। इसके विपरीत, राज्य ना क्षेत्र यात्रिक किया है, उसकी शक्ति बल है एवं पढित जाटल है।""

समाज राज्य से बड़ा अथवा छोटा भी हो सनता है। अपने वड़े हप में समाज राष्ट्रीय सीमा ना अतित्रमण कर सनता है, जैसे—मुसलिम भ्रातृत्व, ईसाई समाज।

^{17 &}quot;An association denotes a group of persons or members who are associated and organized into a unity of will for a common end " —MacIver R M The Modern State p 6

But roughly we may say that the area of the one ■ voluntary co-operation its energy that of goodwill itsmethod that of clasticity while the area of the other is rather that of mechanical action —Barker quoted by Asirvatham op cit, (1964), p 28

राज्य ना उद्देश्य सीमित और समाज ना व्यापन होता है। राज्य का सम्माध केवल उन सामाजिक सम्बाधा से होता है जो शासन द्वारा अपने नी अभिव्यक्त करते हैं जबिन समाज मनुष्या ने सभी उद्देश्या नी पूण नरता है। राज्य ना मुग्य उद्देश समाज में व्यवस्था मी स्थापना नरना मात्र है जिससे व्यक्ति शातिपूवन एव सम्मानपूवन रह सने।

यद्यपि राज्य और समाज में सुस्पष्ट एवं आधारभूत अन्तर है परंतु राज्य एक महत्वपूष सामाजिक सस्या है। राज्य समाज में व्यवस्था स्थापित करता है, समाज को विषयित एवं विश्वलित होने से रोक्या है तथा व्यक्तिया के आवरण की नियमित एवं मयादित करता है। बाकर ने समाज के लिए राज्य के महत्व का वताते हुए लिखा है कि ''समाज राज्य द्वारा समठित रखा जाता है। यदि राज्य समाज को सगठित न रसे तो वह नष्ट हो जायेगा।'''

राज्य व समाज ने अतर को सममना आवश्यन है। इसके अमाव मे व्यक्ति हारास्वत जाता की प्राप्ति सम्मव नहीं है। राज्य व समाज को एन मानना मयनर भूल होगी। इससे राज्य को व्यक्ति के जीवन ने प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेत्र का अधिकार प्राप्त हो जायेगा। समम्रवादी विचारका (Totalitarian thinkers) ने राज्य व समाज मे भेद नहीं क्या है तथा राज्य ने मयक्षेत्र को सीमाएँ निश्चित नहीं भी है। इसन यह परिणाम हुआ कि राज्य अमर है। पर तु यह मत सत्य नहीं है। राज्य भी वनते व नष्ट होते हैं और अनेक समुवाय राज्य की तुलता मे अधिक स्थायी है। उदाहरण के लिए, रोमन कैयोलिक वर्ष । सामा य रूप में परिवार एक स्थायी है।

मनुष्य एक समय मे एक राज्य ना ही सदस्य हो सक्ता है लेकिन नई समुदाया की सदस्यता एक साथ प्रहण कर सकता है। राज्य एव समुदाया की सदस्यता मे नाई अत्तर्विरोध नहीं होता। परन्तु आधुनिक समुदायो द्वारा राज्य की नीतिया को अपने सहयोग एव असहयोग से प्रमायित किया जाता है।

राज्य एवं राष्ट्र (STATE AND NATION)

राज्य एव राष्ट्र कभी-वभी समानार्थी शब्दा के रूप मे प्रयोग विय जाते है। परन्तु इनम अतर है। एक राज्य राष्ट्र हो भी सक्ता है और नहीं भी। 'राष्ट्र' और 'राष्ट्रीमता' का अध मली प्रकार स्पष्ट हो जाना चाहिए। राष्ट्रीयता एक मनोभावना है जो प्राय किसी जनसमुदाय मे समान मापा, सस्द्रति, धम, रीति रिवाज, मौगोलिक सामीप्य, समान दिलिहास, समान जायिक हितो तथा राजनीतिक सहस्य से उत्पन्न होती है। यह आवश्यक नहीं है कि उपर्युत्त एक नुभूति को उत्पन्न करने वाले सभी तत्व इसमें पाये जाते हो। अत राष्ट्रीयता आध्यात्मिक एकता की एक मावना या सिद्धात है जो किसी जनसमुदाय में यह आव उत्पन्न करता है कि हम

¹⁹ Ibid p 28

²⁰ Gilchrist, R N Principles of Political Science, 1930, p 26

एवं साथ रहे। वे पथक होने पर कच्ट का अनुमन करत है। लास्की व दादों में राप्दीयता का अब "उस विशेष एवता स है जो विसी जनसमूदाय का शेप मानवता से पथन कर देती है। समान इतिहास, विजया एवं परम्पराओं वे सामुहिन प्रयास न परिणामस्वरूप इस एकता वा सृजन होता है । उनमे ऐसी सजातीयता वा विकास होता है जो उह एक्ता म जाबद्ध वर देती है। जनवा अपना साहित्य और बला होती है जो अय राष्ट्रा से निस्सादेह पृथव हाती है।" 1

विचारका म 'Nation और 'Nationality दादरो के अथ में मतभेद है और उनका मित्र भित अर्था में प्रयोग तिया जाता है । मुख राष्ट्र (Nation) का अप एक विशेष जाति की जनसंख्या से लगात ह और उसके राजनीतिक सम्पक्ष मे महत्व नही देते, जबिन दूसरे राष्ट्र क अय मे राजनीतिक शासन ना महत्व देत हैं अर्थात राष्ट्र ना नय एकानुभूतियुक्त जनसमुदाय - राज्य से है । राष्ट्रीयता को कुछ विद्वान मावना या सिद्धा त मानते हैं तो अन्य विद्वान राष्ट्रीयता का प्रयोग किसी क्षेत्र विशेष म निवास करने वाले अरपसरयक जातीय जनसमुदाय के लिए करते हैं।" हम 'Nationality' के लिए इस अथ म राष्ट-जाति शब्द का प्रयोग कर सकते हैं।

राष्ट्र की विभिन्न दृष्टियों से परिमापा की गयी है। बगेंस एव लीकॉक ने राष्ट्र की परिमापा वश एव जातीय अथीं (racial and ethnographical sense) मे नी है। बर्गेस के जनुसार राप्ट्र से अथ जातीय एक्ता युक्त जनसमुदाय से है जो किसी एक ही मौगोलिक क्षेत्र में निवास करता हो। लीकाँक के अनुसार राष्ट्र से अय ऐसे व्यक्तियों से है जो स्थान, वश परम्परा एवं भाषा से एक्ता में आबद्ध हा। 19वी सदी में यह धारणा बहुत बलवती हो गयी थी कि एक राप्ट्र-आति का अपना राज नीतिक सगठन हाना चाहिए। इसे ही राष्ट्रीय आत्मनिणय या 'एक राष्ट्र एक राज्य' का सिद्धा त कहा जाता है। बाइस, रेम्से म्योर, विलकाइस्ट तथा हेस की परिमापाली म इस राजनीतिक पहल की अभिन्यक्ति पायी जाती है।

ब्राइस के अनुसार-

"राप्ट्र एव राष्ट्र जाति है जिसा अपने को राजनीतिक निकाय के रूप मे सगठित कर लिया है या स्वत न हाना चाहता है।" 3

हेस के अनुसार---

"एक राष्ट्र जाति एकता एव स्वतान सप्रमुता को प्राप्त करके ही राष्ट्र वनती है।"24

Garner op at p 102

A nationality by acquiring unity and sovereign independence becomes a nation?—Hayes, C.J.H. Essays on Nationalism, p. 5. 24

quoted by Garner op at , p 107

²¹ I asks A Grammar of Politics, 1941, pp 219 20

Nation is a nationality which has organized itself into a political body either independent or desiring to be independent '-Bryce Impressions of South America 1913 p. 424 quoted by Garner op

रेम्से म्योर के शादी से---

''राप्ट्र वह जनसमुदाय है जिसके सदस्य अपने को स्वामाविक रूप से एकता के बुछ ऐसे सूत्रों में बँघा हुआ अनुभव शरते है जो इतने हढ और वास्तविक होते है कि उनके कारण प्रसन्तापूवन साथ साथ रह सकते हैं, पृथक हो जाने पर दु सी होते है और ऐसे लोगों की अधीनता सहन नहीं कर सकते जो उन व घनों के अ तगत नहीं 養 i" s

गिलकाइस्ट के वथनानुसार-

"राप्ट अथ की दृष्टि से राज्य के समीप है , लेकिन राष्ट्र का ज्यापक महत्व है। राष्ट्र राज्य 🕂 कुछ अय है। राष्ट्र का जय है राज्य म सगठित एकानुभृतियुक्त समाज 1^{27 6}

अत राष्ट्र एव राज्य मे अतर है। राज्य के लिए एकानुभूति की मावना आव-इयक नही है जबकि राष्ट्र के लिए अनिवाय है। एक राज्य मे अनेक राष्ट्र-जातिया हो सकती हैं, उनमे एकता का अभाव हो सकता है। उदाहरण के लिए, प्रथम विश्वयुद्ध से पुष आस्टिया हगरी के राज्य मे अनेक राष्ट्र-जातिया निवास करती थी। अत आस्ट्रिया-हगरी का सामाज्य राज्य था परन्तु राष्ट्र नहीं । इनमें से कई राष्ट्र-जातिया प्रथम विज्वयद्ध के बाद स्वता राज्य बन गयेथे। राज्य प्रभुत्व सम्पन होता है। पर त राष्ट्र के लिए यह आवश्यम तत्व नहीं है । कोई जनसमुदाय यदि स्वतात्र होने के लिए सघपरत है तो उसे भी राप्ट कहा जायेगा।

राज्य व सरकार (STATE AND GOVERNMENT)

सामा यत राज्य व सरकार मे भेद नही किया जाता है। सामा य-जन बहुधा 'राज्य' व 'सरकार' शब्दी का प्रयोग एक ही अथ मे करते हैं। हाँब्स ने ती राज्य व शासन का प्रयोग समान अथ में किया है। निरक्त शासन राज्य व शासन में अन्तर नहीं करते । राजत त्रीय व्यवस्था में अधिकाश शासक अपने व्यक्तित्व को ही राज्य मानते थे। फास का राजा लुई १४वा कहा करता था वि 'मैं ही राज्य हैं।' पर त राज्य व शासन मे आधारभूत अतर है। सरकार राज्य का केवल एक तन्त्र है। विधिया को कियाबित करने ने लिए राज्य ने पास सर्वोच्च सत्ता होनी चाहिए। स्टाग ने अनुसार यही सरवार या शासन वहलाती है। सरवार राज्य वा या (machinery) है। बिना उसके राज्य वायम नहीं रह सकता क्यानि शासन मगठिन शक्ति है। अत शासन वह सगठन है जो सप्रमु की शक्तिया का उपनोग करता है। " रसो के अनुसार सरकार जीवित उपकरण (living tool) है। साम्बी सरकार को राज्य का अभिकर्ता

27

Ramsay Muir Nationalism and Internationalism, 1917, p 31 "Nation is very near in meaning to State, the former has a broader significance. It is the state plus something else that of the unity of the people organized in one state christ. Principles of Political Strong, 1930 p. 26 Strong, C F Modern Political Constitutions 1963 P-



ते विभिन्न प्रवार होते हैं, असे राजत त्र, गुलीनतत्र, प्रजातत्र । प्रजा तत्र म भी अध्यक्षात्मव एव ससदीय सरकारे होती हैं। इन सत्र वे सक्षणा म अत्तर है जबिंच भूगण्य, जनसंख्या, शासन एव प्रभुत्य राज्य में चार अनिवाय तत्व हैं।

(vi) सरकार वे अभाव म राज्य की वल्पना नहीं की जा सकती है तथा सरकार राज्य पर आधारित है।

हमन फाइनर ने अनुसार ' शासन मानवीय सहयोग, सत्ता वे प्रदत्तीवरण, स्वरूप एवं पद्रतिया ने विभिन्न प्रकारा से बना है। यह शासन की शरीर-रचना है। शासन की सस्थाओं का व्यक्तिया द्वारा निर्माण एवं संशोधन आनार प्राप्ति और अपने मा'य या स्वीवृत बतव्यो की पूर्ति वे लिए किया जाता है।''31 मानव-सभ्यता वे विकास म शासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। शासन के अमान की कल्पना या विचार एक छन मात्र है। फाइनर शासन वे दो माटे माग मानता है (1) राजनीति की प्रतिया (Process of Politics) एव (2) प्रशासन प्रतिया (Process of Administration)। राजनीति की प्रश्निया का तात्पय सामाजिक इच्छा (social will) के उदय, विकास एव उसवे परिष्कृत होने की प्रक्रिया से है जिससे समाज द्वारा स्वीकृत नियम या विधि का निर्माण हो सबे। इस प्रश्रिया के साथ-साथ समाज के सदस्य सामाजिक इच्छा के निर्माण में लिए आवश्यक समय, बक्ति एव धन का बलिदान करते हैं तथा सामाजिक इच्छा को सहयोग देने एव उसे पुष्ट करने के लिए वाखनीय आत्म नियानण भी रखते हैं। इसका परिणाम होता है सामाजिक इच्छा एव शक्तिका मण्डार । उपयुक्त व्यक्तिया एवं यानिक, क्षेत्रीय तथा पद्धतिमूलक तरीको द्वारा आवश्यक शासकीय सेवाजा को सम्पादित करने एव अकलब्यपरायण व्यक्तियो से दायित्व एव कतव्य कराने के लिए सामाजिक इच्छा व शक्ति के प्रयोग को प्रशासन कहते हैं। राजनीति एव प्रशासन म राजनीति का स्थान प्रथम है। प्रशासन शासन के राजनीतिक पहलु के अधीन है एव ऐसा होना भी ठीक है। अत फाइनर के अनुसार राजनीति +प्रशासन = शासन है। 35 आधूनिक समाज के व्यक्तिया की आर्थिक एव सामाजिक पुष्ठभूमि अत्यधिक

जिटल है। बढ़े आकार एव अधिक जनसरया बाले राज्या के कारण समस्याएँ जिटलतर होती जाती है। करमाणकारी राज्य की धारणा ने धासन के वाधित्वों में असाधारण वृद्धि की है। मुक्त व्यापार नीति का युग समाप्त हो चुका है। समाजवाद का शखनाद हो रहा है। अविविश्वत एव विवासवारी अथव्यवस्था वाले देशा में आधिक और सामाजिक विपनता वा उम्मलन शासन का प्रधान दाधित्व है। आधिक नियोजन हारा इस देशव्यापी सामाजिक विपनता एव अभाव को मिटाना चाहते है। अत शासन के अप के सामाजिक विपनता का व्यक्त हो आधिक सामाजिक विपनता का उस्ते हो अधिक सामाजिक विपनता एव अभाव को मिटाना चाहते है। अत शासन को अप उत्तरादक एव विवरक के दायित्वों को गी निमाना है। प्रदन है, क्या शासन को वहुद बहुदेशीय दायित्वों को निमा सकता है?, वया शासन की शर्तिकों

³⁴ Finer H Theory and Practice of Modern Government, 1956, p 6
35 'Government ■ politics plus administration' —Ibid, p 7



राज्यो एव सविधानो का वर्गीकरण [CLASSIFICATION OF STATES AND CONSTITUTIONS]

राज्य एक साबभीम सत्य है। राज्य के अनेक प्रकार हैं। राज्य की प्रकृति एव उत्पक्ति के सम्बन्ध म जिस प्रकार विभिन्न मत प्रचलिन हैं उसी प्रकार राज्य के वर्गी करण के सम्बन्ध में भी तीज विवाद हैं। राज्य के वर्गीकरण सम्बन्धी दो मुख्य प्रका हैं

(1) राज्य में विभिन्न स्वरूप को ब्याफ करने के निए 'राज्य का वर्गीकरण' या 'द्यासन का वर्गीकरण' पदा भ से किसका प्रयोग उचित है ?

(2) राज्यो ने वर्धीनरण का सत्तोपजनक एव वैज्ञानिक आधार क्या हो सकता है $^{\circ}$

राज्य या ज्ञामन के वर्गीकरण में से किम पद का सम्बोधन राज्य के वर्गीकरण के लिए उपयुक्त होगा ? इस प्रश्न के सम्बन्ध में विद्वानों म प्याप्त मतभेद है। विलोधी, गानर, गिलकाइस्ट 'मरवारा का वर्गीकरण' पद का प्रयोग उचित मानत हैं । विलोधी का मत था कि 'राज्या का वर्गीकरण' नामक काई वस्तु सम्भव ही नही है। अपने मूल तत्वों में सभी राज्य समान होते हैं। प्रत्येक राज्य के लिए प्रभूता अनिवायत आव-इयक है। लीकाँक बादि विद्वान विलोधी की उपर्यक्त धारणा से सहमत उही हैं। वे 'सरकारा के वर्गीकरण' की अपेक्षा 'राज्यों के वर्गीकरण' या 'सविधानों का वर्गीकरण' पद का प्रयोग करना उचित मा रते हैं। विलोगी एव गानर आदि विद्वाना के इस तक मे लीवॉब सहमत नही हैं कि शामन के समठन एवं स्वरूप तथा उद्देश्य द्वारा ही राज्य को जाना जा सकता है। डाँ आशीर्वादय ने लीकाँक से सहमित ध्यक्त की है। उनका तक है कि शासन राज्य का अभिकर्ता या यात्र है। विना राज्य के शासन की बरुपना ही नहीं की जा सकती 12 सी एफ स्टाम ने भी 'मविधानों का वर्गीकरण' पद का प्रयाग विया है। असिद्ध युनानी विद्वान अग्स्तु न भी अपनी रचना पौलि-टिनस' में सविधाना का वर्गीकरण पस्तुत किया है। इसी परम्परा का अनुगमन करते हुए इस पुस्तन में 'राज्यो एव सविधानो का वर्गीकरण पद का प्रयोग किया गया है। सविधान के स्वरूप म परिवतन जाने पर राज्य के स्वरूप में स्वत ही परिवतन आ जाता है ।

हितीय प्रश्न यह है वि राज्या ने वर्षीनरण ना सातीपजनन आधार क्या हो सकता है ? सभी राज्य अपनी प्रकृति, विधिक विशेषता एव यूत्र उद्देश्या नी हिन्द से

¹ Asirvatham E Political Theory (1965), p 342

14 | आधुनिक शासनतात्र

समान होते हैं। जनसंख्या, भूमि, सरकार एवं प्रभूत्व सभी राज्यी वे तत्व हैं तथा अनिवायत पाय जाते हैं। अत राज्यों का वर्गीकरण असम्भव है। जनसंख्या एव भूमि राज्य की बाह्य विशेषताओं को अभिव्यक्त करते हैं। इनके आधार पर सातोपजनक एव वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत करना सम्भव नही है। गेटिल बाह्य तत्वों के आधार पर राज्यों के वर्गीकरण को विवरणात्मक मानता है तथा उन्हें वर्गीकरण के कम महत्व के आबार मानता है। जनसरया एव भूमि ने आधार पर राज्य कमश रम एव अधिक जनसरया वाले राज्यो तथा छोटे एव वडे राज्यो मे वर्गीकृत किये जा सकते हैं। कुछ विचारको ने आकार (size) की हर्ष्टि से राज्यो को नगर-राज्य, राष्ट्र-राज्य एव विश्व राज्य तथा साम्राज्यों मे वर्गीकृत किया है। पर तु यह केवल राज्या के ऐतिहासिक रूपो का विवरण है न कि राज्यो का तकसगत वर्गीकरण । राज्यो की कमजोर एव शक्तिशाली राज्यों में भी वर्गीकृत किया जाता है। सप्रभुता के आधार पर मी राज्यो का वर्गीकरण किया गया है—पूण प्रमुमत्तायुक्त राज्य, आशिक प्रभु सत्तायुक्त राज्य सरक्षित राज्य, तटस्य राज्य एव अधीनस्य राज्य । सैनिक, असैनिक, असम्य सम्य बजदार एव साहकार राज्य का मी वर्गीकरण उपलब्ध है। इस प्रकार के वर्गीकरणो का राजनीतिशास्त्री के लिए कोई महत्व नही है क्योंकि ये तकसगत एव वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं हैं।

जिलिनिक एव वर्गेस ने मतानुसार राज्या ने वर्गीनरण का श्रेंग्ठतम आधार यह सिदात है नि राज्य की इच्छा किस पकार निर्मात एव अमिन्यस्त होती है अपात प्रमुसत्ता राज्य में कहा अधिष्ठित है? इस सिद्धात ने आधार पर ही अरस्त ना परम्परात्त वर्गोकरण—राज्यत्र, कुलीनतात एव लोकता—आधारित है। गेटिल इस वर्गोकरण को राज्य के सम्गठन पर आधारित मानता है। अरस्त ने वर्गोकरण का जाधार सिद्धात न होकर सरया एव माना है। कुलीनतात एव लोकतात एक दूसरे में इस प्रकार तिरोहित हो जाते है कि उनमें अतर करना कठिन है। अनक राज्यों म विमान तथों ना मिश्रण पाया जाता है जह अरस्त के वर्गोकरण को आधुनिक राज्यों पर लागू करना भामक है। अरस्त ना वर्गीवरण भी यथाय म केवल सरकार ना ही वर्गोकरण है वर्गोक यह राज्य के सगठन नी प्रवृत्ति (या शासत्त) पर आधारित हो ही वर्गोकर हो यो स्वांच के सगता है। राज्य नी सर्वोच्च शासि एव

² Gettell R G Political Science 1956 p 191

^{3 &#}x27;To (Aristotle's) classification several objections may be urged. The basis is quantitative and numerical rather than one of principle. Aristocracy and democracy shade off into one another in such a way that a clear distinction between them in hard to make. Many states combine elements of various forms and any attempt to apply this classification to existing states would lead to wide difference of opinions. Finally, this classification also is in reality based upon the nature of the states organization and is actually a classification of governmental forms. — Ibid. p. 193

इच्छा इसके द्वारा अभिव्यक्त होती है। शासा के स्वरूप म घोडा सा परिवतन व्यापक रूप से राज्य के स्वरूप को प्रमावित करता है।

मेटिल ने इस सत्य यो ध्यक्त यरते हुए वहा है वि "राज्य वी प्रमुख विद्येपता उमयी राजनीतिर एव विधिय प्रवृत्ति है। यह उमरे दासन-सगठन मे अभिव्यक्त होती है। अत राज्या वा पूण सत्तोपजनव वर्गीवरण दासन वे स्वरूपा के अतर एव समानताआ पर आपारित होता है। अत यह राज्या वा नही अपितु सरवारा वा वर्गीवरण है। यह वहा जाता है वि राज्या वा अस्तित्व मरवारा वे द्वारा अमिव्यक्त होता है वे राज्या वा अस्तित्व मरवारा वे द्वारा अमिव्यक्त होता है और अप पित्री ज्वित आधार वो ढूढना विजन है। अत सरवारा वा वर्गीवरण है। यह पढ़ा वा वर्गीवरण है। विजये वर्गीवरण है। वर्गीवरण हो। वर्गीवरण हो। वर्गीवरण हो। वर्गीवरण हो। वर्गीवर

राज्य वर्गीकरण की विभिन्न योजनाएँ

राज्यों ने वर्गनिरण ना सबते प्राचीन उल्लेग पूनानी इतिहासनार हिरोडोटस नी रचना में मिलता है। यह राज्य ने तीन प्रनार मानता है—एनतात्र या निरकुत-तात्र, युलीनतात्र एय लोगतात्र । हिरोडोटस ने अनुसार निरकुत सासक के आततायी एव अत्याचारी प्राप्तन ने फलस्वरूप उसना पतन हो जाता है तथा लोकतात्र नी स्थापना होती है जिनमे विधि के समक्ष सभी समान होते हैं। लेकिन लोकतात्र प्रीप्त हो भीडतात्र या समूह ने यासन में परिवर्तित हो जाता है। अत हिरोडोटस ने अनुसार कुछ निर्वाचित व्यक्तियों ना भासन सदा अच्छा होता है पर तु एव योग्य एव श्रेष्ठ व्यक्ति ने शासन से नोई सासन श्रेष्ठ नही होता ।

सकरात का वर्गीकरण

मुकरास लोन ता नका घोर नि दक था। वह शासन को कला मानता था। कला के लिए ज्ञान अपक्षित है। लोक ता न ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता क्यों कि विधानमण्डल एक अधिकारी अयोग्य हाते हैं। सुकरात के अनुसार शासक में प्रजा के प्रति करवाण की नि स्वाय मावना होनी चाहिए जो एक निरकुश शासक म सम्मव नहीं है। मुकरात ने राज्यों को दो मागों में बाहा है—एक, जिसम शासक नि स्वार्थी एवं युद्धिमान होते हैं, और दूसरे, जो स्वार्थी एवं पूरत होते हैं। उसने शासन के तीन मुख्य रूप माने हैं। एक तान, हुलीनतान व लोकतान ता असे प्रतापन के तासन के तान न के उपविमाग अरुधे एवं दुदे शासनों के रूप में किये हैं। इस प्रवार शासन के पाच मुख्य माग है।

एकतान (Monarchy) में राजा प्रजा की अनुमति से शासन करता है एव विभि का सम्मान करता है। यदि राजा उत्पोठक एव अत्याचारी हो जाता है तो वह एकतान का विकृत रूप होता है। उसे अत्याचारतान (Tyranny) कहते हैं। यदि किसी राज्य का शासन एक वंग विजोग के योग्य एवं सक्षम व्यक्तियों के हाथों में होता है

^{4 &#}x27;It may be urged that since states manifest their existence only through their governments and since on no other basis can they be properly distinguished, a classification of governments is in essence a classification of states "—Gettell Ibid, pp 19192

⁵ Herodotus History, Book III, Chaps 80 82

तो वह सासन हुलोनता (Aristocracy) होता है। यदि इसवे विपरीत शासन स्वार्थी धनिक वग के हाथों में है तो वह अल्पत म (Oligarchy) कहलाता है। सुकरात लोक ताम (Democracy) को अयोग्य एव क्षमताहीन व्यक्तियों का शासन मानता था। उसने एकता म व नुलीनताम को श्रेष्ठ शासन बताया है और श्रेष तीन को निहण्ट शासन। स्केटी का बर्सीकरण

प्लेटों ने राज्य के वर्गीनरण की दो योजनाएँ प्रस्तुत की—एन 'आदश राज्य'—
रिपिल्लिक (The Republic) में और दूसरी 'राजपुत्र'— स्टेटसमैन (The States man) में । रिपिल्लिक म प्लेटो सर्वोच्च प्रस्तय (Idea) या विवेच की प्रमुता स्थापित करता है । इसे वह विवेचता (Ideocracy) की सजा देता है। यह पूण जान (perfect knowledge) मा राज्य है। जान ही इसमें सप्रमु है। प्लेटों के अनुसार ऐसा आदश राज्य भूतल पर असनम्ब है। फिर भी वह उसे ऐसा आदश मानता है जिसमा परित्यान नहीं किया जाना चाहिए। रिपिल्लिंग में बर्जित आदश राज्य में वह दशन को शासन मानता है। दशन विशुद्ध जान है अत वह दाशनिक शासक का विधान करता है। इसे हम आदश राज्य ने बाह्य राज्य या मुलीनता न भी सजा दे मक्ते हैं। प्लेटों ने इस आदश राज्य के आधार पर यथाय राज्य के निम्न क्यो में नम्या परित्यतन का शलिल क्या है। कावश राज्य का सैनिक राज्य हो जाता है। वितान अल्यतन न का प्रत्य का शिनक लत्यत (Oligarchy) में पतन हो जाता है। अतिक शकर न में पतन हता है कीर उसकी स्थान लोकतान के लेता है जो स्वय में पतित हो जाता है।

Sabine A History of Political Theory 1957 p 76
 Gilchrist Principles of Political Science 1930, p 227

राज्यसत्ता घारण करने वालो को सक्ष्या	विधिपालक राज्य	राज्य जिनमे विधियो का पालन नहीं होता
एक व्यक्ति का शासन	राजतन	अत्याचारत न
(Rule by One)	(Monarchy)	(Tyranny)
कूछ व्यक्तिया का शासन	कुलीनत न	अल्पतान
(Rule by Few)	(Aristocracy)	(Oligarchy)
बहुतो का शासन	उदार लोकतात्र	उग्र लोकत"न
(Rule by Many)	(Moderate Democracy)	(Extreme Democracy)

प्लेटो कृत 'दि लॉज' (The Laws) नामक ग्राथ मे वर्णित राज्य विधि प्रधान राज्य है। प्लेटो लॉज' वर्णित राज्य म कानून की सप्रमुता को मानवीय कमजोरी के रूप में स्वीकार करता है। प्लेटो ने 'रिपब्जिक में वर्णित आदश राज्य में विधि को वहिप्कृत कर दिया था, लेकिन 'लॉज' म झान के मूर्तिमान रूप दाशितक राजा का स्थान वह विधि को दे देता है। यही उसका उप आदश राज्य है। विधिपालक राज्या में प्लेटो लोकतान को सर्वोत्तम सममता है यद्यपि विधि का पालन करने वाले राज्यों में वह निम्त श्रेणी में हैं । लोकतान के दोना रूप धनिक अल्पतान की तलना में अच्छे हैं।

अरस्तुका वर्गीकरण

राज्यों के वर्गीकरण की प्राचीन योजनाजा मे अरस्तू का वर्गीकरण सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अरस्तू प्लेटो के उपर्युक्त वर्णित वर्गीकरण से काफी प्रमावित था। अरस्तू का वर्गीनरण प्लेटो की भाति दो सिद्धातो पर आधारित है-प्रथम, सख्या का सिद्धात अर्थात प्रमुसत्ता को धारण करने वाले शासक वग की सख्या, एव द्वितीय, ज्हेहय का सिद्धात अर्थात उहेश्य जिसके लिए शासक-वग प्रमुसत्ता का प्रयोग करता है। इसमे अरम्त् अपना तीसरा सिद्धात-समय-चक्र का सिद्धात-जोड देता है। स्मरणीय है कि अरस्तु इतिहास का विद्यार्थी या और उसके क्यन एव निष्कप प्रयवेक्षण पर आधारित थे।

राज्यसता नो धारण करने वाले एक व्यक्ति, कुछ व्यक्ति एव बहुत-से व्यक्ति हो सकते हैं। उद्देश्य की दृष्टि से उसने राज्य को दो वर्गों-अच्छे एव बुरे या सामाय एव विकृत राज्य-मे वर्गीकृत किया है। सामा य राज्य वह है जिसमे झासर वग द्वारा सत्ता का प्रयोग स्वाय रहित होकर सामा य कल्याण के लिए किया जाता है। इसने विपरीत, शासक वग जब निजी स्वाय के लिए ही सत्ता ना प्रयोग नरते हैं तर वह राज्य का पतित या विकृत रूप होता है। शासक-वम जब सर्वाहताय शासन करते हैं तो अरस्त एक व्यक्ति ने शासन को एकत त्र, बुछ व्यक्तिया के झासन को कुतीन तत्र एव बहुत से व्यक्तियों के धासन की सत्यानिक तीवतन्त्र भी सना दता है। नेक्नि जब शासा द्वारा सत्ता का दुरुपयोग निया जाता है और केपल शासको के स्वायों नी पूर्ति नी जाती है तो सामाय शासन श्रमश अत्याचारत त्र, अल्पतान एव भीडतान में परिणत ही जाते हैं। यह राज्य ने विश्वत रूप है। अरम्तू ने उपयुक्त वर्गीकरण नी तालिना निम्त्रत है

411074 11 (117411111111111111111111111111111		
सविधान का	शासन का सामा य रूप	शासन का विकृत रूप
स्यहप्	(Normal, Good or	(Bad or Perverted form)
शासक वग	True form)	नेवल शासक-यग के निजी
की सख्या	सामा य हित मे शासन	हित में शासन
एक व्यक्ति	राजत न	अत्याचारत न
काशासन	(Monarchy)	(Tyranny or Despotism)
कुछ व्यक्तियो	कुलीनत न	अल्पतान
का शासन	(Aristocracy)	(Oligarchy)
बहुसख्यका	सवैधानिक लोकतान	লাকর ন
का शासन	(Polity)	(Democracy)

अरस्तू का यह वर्गावरण व्यापक अध्ययन पर आधारित है। उसने अपने समय के 158 यूनानी एव अय सविधानों का अध्ययन किया था। उसना मत था कि सरकार में स्वाप्ते परिवतन एक कम में आते हैं। वास्तव में, इस वर्गीकरण के द्वारा उसने सरकारों में स्वाप्ताविक विकास मने व्यक्त करने का सफल प्रवास किया है। अरस्तु का वयन है कि सवस्त्रयम शासन वा स्वस्त्र करने का सफल प्रवास किया है। अरस्तु का वयन है कि सवस्त्रयम शासन वा स्वस्त्र कारण यह था कि पहले नगर छोटे वे और उनमें भूण सम्प्रव्यक्ति कम में, अत वे ही राजा नियुक्त किये जाते थे। वे परोपकारी भी होते थे और सज्जन पुरुपो द्वारा ही करवाण सम्मव है। लेकिन जब समान गुण सम्प्रव्यक्तियों की सर्या में बुद्धि हुई और प्रत्येच के द्वारा दूसरे की श्रेष्टता को अस्वीवार किया जान लगा तो जन्म राज्य की स्थापना की इच्छा उत्पत्र हुई और उत्येच के स्थापना की इच्छा उत्पत्र हुई और उत्येच के स्थापना की स्वाप्त का समान का नगरण बना अत अस्पत्र का जन कर से अपने को धनी बनाने लगा धन सम्मान का नगरण बना अत अस्पत्र का जन्म छम अपने को धनी बनाने लगा धन सम्मान का नगरण बना अत अस्पत्र का जन्म वा अस्पत्र का स्थापना की सर्या म स्रोप्त की स्थापना के स्थापना के स्थापना के स्थापना के स्थापना के स्थापना स्थापन के स्थापना को स्थापना का स्थापना का स्थापना का स्थापना का स्थापन का स्थापना का स्थापन का स्थाप

करस्तू में सरकारा के परिवतन चन द्वारा तत्कालीम यूनानी मगर राज्यो भी राजनीतिक दशा को प्रतिविभिन्त विचा गया है। जस्सू के राजनीतिक परिवतनी के प्रम ने क्रमुसार एक व्यक्ति वा शासन जब अध्य होकर अस्त्याचारत में परिणत हो जाता है तो पाठे-से व्यक्ति सामाय कल्याण के माव से प्रेरित होत है और रासन पर स्वत्य स्थापित कर लेते हैं। यह नुख व्यक्तिया का सामाय कल्याण म

⁹ Aristotle The Politics Bk III Chaps VII and XV, Edited by J A Sinclair, 1962, pp 101 149

जुलीनतत्रिय पासन है। सेनिन यह भी दीघजीवी नहीं रहता। कुछ व्यक्तिया ने सातन या भी भार होना अस्वामाविन नहीं है। बुलीनतत्र प्रामित एव भार तरीनों में सता या निजी स्वाये म प्रयोग करते हुए अपनी सहार नायम रंगता है। इसे अरस्त अरलंत म रहता है। अत म इस पृष्णित झामन ने विरद्ध जन विद्रोह होता है और अल्पतम्म ने स्वाय वहुसस्यमा या झासन या सवैधानिन सोमतम्म ते लेता है। अरस्त में अनुभार सवैधानिन सोमतम्म का भी थी। म पतन हो जाता है। वह सम्जलन हिताय झासन न रहन र बहुसम्यमो ना झासा हो जाता है। समम अराजनता एव स्वच्य दस्त मा साधान्य छा जाता है। इसे भीनताम ने सिता दो जा सकती है। अरस्त इसे लोमतम्म प्यवित व्यवस्था व झात्ति में स्थापना मरता है। इस प्रमार परिवतन वम पूण होता है स्वायन व्यवस्था व झात्ति में स्थापना मरता है। इस प्रमार परिवतन वम पूण होता है स्वायन वोन च प्रमार हो जाता है। स्मरणीय है व अरस्त वा मुद्ध व्यवितया ने झात्त से आप मारत है आरस्त हो आरा है। स्मरणीय है व अरस्त वा मुद्ध व्यवितया ने झात्त से आप निमनो के झात्त में मिनना ने झासन से है एव वहस्य ने शासन से क्षा निमनों के झात्त से है प्रमार ने सारत से भावता ने झात्त से है एव वहस्य वे झारत से आप निमनों के झात्त से है एव

आलोचना--अरस्तू ने वर्गीवरण की निम्न प्रमुख आतोचनाएँ की जाती है

- (1) प्रो सीले में अनुसार अरस्तू ना वर्गीनरण आधुनिन राज्यों में लिए अनुप्युक्त है। 10 मिलप्राइस्ट ने इस निचार को निम्न शब्दों में स्थवत निया है— "आधुनिक सरकार। में लिए अरस्तू का वर्गीकरण अपर्याप्त है लेकिन परवर्ती सभी वर्गीकरणों को यह ऐतिहासिन आधार प्रदान करता है। 1111
- (2) अरस्तु वा वर्गीयरण मानर के अनुसार ''सरकारो के वर्गीकरण के एप में भी उपयुक्त नहीं है नयोगि इतना आधार कोई वैज्ञानिक सिद्धात नहीं है, जिसके अनुसार सरकार की भूल विज्ञेपताओ एव समठन के रूपों में स्पष्ट अंतर किया ता सके।' गानर के अनुसार यह राज्यों का वर्गीकरण है, न कि सरकारों का वर्गीकरण !
- (3) जर्मन विचारन बाँन मोल के अनुसार इस वर्गीकरण का आधारम्त सिद्धात्त सावयदी न होकर गणिनीय और गुणमूलक न होकर सख्यामूलक है। 18 उदा हरण के लिए मुलीनतात्र व लाकतात्र में केवल सख्या का अत्तर है।

^{10 &}quot;He knew only city states and they were marvellously unlike" the country states of modern times and therefore any classification which would put them in the same category would be of little value "-Seeley Introduction to Political Science, p 49, as referred by Garner Political Science and Government, p 225

¹¹ Gilchrist Principles of Political Science, 1930, p 228

¹² Garner op at, p 225

¹³ Von Mohi Encyclopedia of Political Science, p 111, quoted by Garner op cit p 225

- (4) विलसन का मत है कि बूजीनतात्र अब विकास-चल से हट गया है और एकता शीय व्यवस्था के बाद ही लागतात्र की स्थापना हो जाती है।14
- (5) सीकॉव¹⁵ ने अनुसार अरस्तू ने वर्गीकरण का प्रयोग सवधानिक एव सीमित एवतात्रीय राज्यो म नही तिया जा सकता । यदि लागतात्र से अय ऐसे शासन से है जिसम सत्ता जनता ने हाया मे होती है और यदि दो देशा ने शासनो ने सगठना पर घ्यान न दिया जाये तो जिटेन एव सयुक्त राज्य अमेरिका लाकत य की श्रेणी मे आते हैं। इसके विपरीत, त्रिटेन मे राजतात्र है बत अरस्तू के वर्गीकरण के अनुसार वह एकत व ने आतगत आता है। ऐसा करना केवल औपचारिक दृष्टि से ही ठीक होगा, व्यावहारिक रूप मे नदापि उही।
- (6) अरस्तू ने वर्गीकरण में सधीय एवं असधीय राज्यों का भेद नहीं रखा गया है और न विधानमण्डल एव वायपालिका के वैधानिक सम्बाधी पर आधारित शासन व्यवस्थाओं में अतर को स्पष्ट किया गया है।
- (7) अरस्तू वा वर्गीवरण मिश्रित शासन व्यवस्था वाले देशो पर लागू नही होता है। प्रो सीले के अनुसार इगलैण्ड का सविधान तीनो शासन-तात्री वा सुदर मिश्रण है । इगलण्ड के सविघान में राजा है, लॉडसमा दुलीनत त्र का प्रतीक है तथा लोक्समा लोक्तत्त्र का प्रतिनिधित्व करती है। अरस्तू का वर्गीकरण ऐसे राज्य पर लागू नही हो सकता।

समीक्षा—वॉन मोल की उपयुक्त आसो तना का प्रत्युत्तर वर्गेस ने दिया है। वह वॉन मोल की आलोचना को आरुतित, अधुद्ध एवं असावधानीयुक्त मानता है। वर्गेस के अनुसार अरस्तू का वर्गीकरण अही सक राज्यो के वर्गीकरण का आधार है, उचित व तकयुक्त है । वर्गेस इस आलोचना को स्पीकार नही करता कि अरस्तू का वर्गीकरण देवल संख्यामूलक है, या वह सावयवी या गुणात्मव नही है। उसवा तक है कि सख्या एव अनुपातो (proportions) का प्रयोग तो केवल यह सिद्ध करने के लिए क्या गया है कि जनता मे राज्य सम्बन्धी जागरूकता शनै शनै कसे ध्यापक होती है एव क्तिनी मात्रा मे उसका विकास होता है। अत राजनीतिक चेतना से युक्त व्यक्तियो नी सख्या तथा उनने द्वारा राज्य एव शासन ने कार्यों में भाग लेने के कारण राज्य मा सावयवी स्वरूप निश्चित होता है।

बरस्तु द्वारा शासन के उद्देश्य के आधार पर सामा य व विशृत राज्यों में भेद शासन ने गुणात्मक पहल पर वल देता है।

अरस्तू की मून्य समस्या यह थी कि गमे राज्य के स्वरूप की खोज की जाय

¹⁴

¹⁵

Wilson op est, p 578 Leacock Liements of Political Science 1929 pp 112 13 Burgess as quoted by Garner op est, p 225 (Burgess Political Science and Constitutional Law p 72)

जिसस परिवतन-चंक का अत ही जाय। मध्यम का श्वासन, जिसे वह सर्वधानिक 4 विषय पार्षपान नाम । जा प्रश्नाम । जानमा पार्म पार्थित स्विधा विकास स्वा इसे वह मिश्चित सविधान (Mixed राज्यो एव सविधानी का वर्गीकरण | 21 Constitution) की सना देता है। •

बरस्तु ने पहचात सममा 1500 वर्षों तक उसी क सिंद्यां तो के आधार पर विद्वान राज्या का वर्गीन रण नरते रहे हैं। विसेरो पोलिवियस मैकियावेली, वोदा, जान विद्वान राज्या का वंभाव रण व रत रहे हैं। विद्यारा भारताव्यत भारताव्यत भारताव्यत, भारता, भारत, भारता, स्तो आदि सभी विचारक इस सम्बंध म अरस्तु से प्रेरणा तेते रहे हैं। आधुनिक विद्वानों के वर्गोंकरण में भी अरस्त्र के विद्वा तो की स्पष्ट मत्व दिलायी देती है। विधाना प्रभावत्वा न गा अरहा मा गावधावा पा हपण्ट कवाम विकासा वता हा अरह्म के बाद भी अनेक विचारका ने राज्या को वर्गीहत करने का प्रयास किया है। अय विचारको के वर्गीकरण

भोतिबियस ने राज्यों के परम्परायत वर्गीकरण को ही स्वीकार किया है। वह प्लेटो एव अरस्तू वे इस सन्व छ मे प्रमावित है। राजत न, जुलीनत त्र एव प्रजान न को बहु राज्यो का शुद्ध या सामाय स्वरूप मानता या तथा अत्याचारत न अस्पतः या वह राज्या मा छक्ष या धामा म रम्पन मान्या मा धमा व्यवसार प्रव मा सामा य रूपा के बाद पुत्र माच्या प्रदेश एक का व्यवस्था प्रदेश हैं। असे राज्या के परिवतन-बक्रकम में आते रहते हैं। असे राज्या के परिवतन शा कम राजत न, अत्याचारत न, हुलीनत न, अल्पत न, लावत न एवं मीडत न है। विरोध ही भीडत न के अयाय एवं अत्याचारा का विरोध करते के लिए एक पाहन प्रभाव हा भावत न भाव प्रभाव प्रभाव के समयन से वह शासन पर प्रभुत्व स्था पित कर लेता है। एक चक्र के प्रण होने पर दूसरा चक्र चलने लगता है। शासन में स्थिरता लाने एव परिवतन वक को रोकने के लिए पीलिवियस मे

मिश्रित संविधान की बारणा को उपस्थित किया है अर्थात विभिन्न शासन प्रणालियो के थेठ तत्वा का मिश्रण किया है। उसके अनुसार शासन म अवरोध एवं संचुलन (checks and balances) की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे शासन प्रवासी को प्रिंच करते वाले तत्वो का विरोध दूसरे तत्व करते रहे एवं उसे विनास से वचाते रहे। पोलिवियस के अनुसार ब्रुनानी विभिवत्ता लाइक्ट्रवस (Lucurgus) ने स्पार्ट के बासन में यह व्यवस्था संफलतापुत्रक की थी। गणत नीय रीम के मिश्रित सविधान की पीलि-न थर ज्यारचा क्रमण्याप्तवम का था। गयत नाथ राज माधावत वाधवाम का माध्य विसस ने भूटि भूटि प्रस्ता की है क्योंकि इससे रोम म स्थिरता स्थापित हो समी थी। विषय । हार हार क्षावा का ह वयाक रवच राज न त्यरवा स्थापव हा चना ना । रीम के मित्रित सैविद्यान में तीनो प्रकार की सरकारों का सम्मिश्चण था। नॉसत (Consuls) राजत के सिंहात का, सीनेट कुलीनत न का तथा संसेचला लोकतन ्रिसहातो का प्रतिनिधित्व करती थी और एक अग हुसरे पर अवस्था का नाम करता था। विरणामस्त्रहण स्थायित्व सम्भव ही सका था।

यद्याप स्वेटी एवं अरस्तु ने मिश्रित सविधान में वर्षा नी है पर तु पोतिवियस ने सवप्रपम रोमन साम्राज्य के अनुमन के आधार पर जसके गुणा की विसद् व्याख्या न वनअपन रामन वाझाज्य व लागुनव व लागार पर जवक गुणा वा विवाद व्याच्या की और अंबरोध एवं संन्तुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन निया। इतिम के अनुसार का बार जबराज पत्र पानुभाग । माधा प्राण्य वास्त्रका राजा । ज्यास्त्र प्राण्य प्राण्य प्राण्य प्राण्य प्राण्य प् प्राप्तन की व्यक्तिरता दूर करने के लिए स्तेटो एवं अस्तू नं विजित सामन प्रणालिया

N

र तत्वा रा सम्मिश्रण वरा रा गुभाउ तिया है सितु पालिदियम स्थापित र दिए सामा वे तीमा श्रमा वे परस्पर विरोध या आउस्यत मारता था ।¹⁷

स्मरणीय है नि पालिवियस में उपयुक्त निष्तर्गों का सम्बन्ध राम के गण राज्य की विदोध साम्रा व्यवस्था ने ही है।

सिसेरों ने मी मिश्रित सविधा तथा अवरोध एव स तुलन के विद्वान मी मुक्तकक से प्रदासा की है। रोमन विचारा मिसरों की पालिविधम की मीति इस क्षेत्र म वोई मीतिक देन नहीं है। पिमरों के बाल म पालिविधम द्वारा प्रगासित रोमन गणराज्य पतनो मुख्य था। पोलिविध्यत के मिश्रित सर्थियान एव भासन प्रणालिया के परिवतन-अन ने सम्याध म सिसेरों ने उसरा सामायत प्रतासा कर तुरारण किया है। उसने एव अतिरिक्त मत भी प्रस्तावित किया है। उसने सासन के ती। अया का तीन सिद्धान्तों का प्रतीक माना है। वा स्वल्व (राजतान) सस्ता के मिद्धान्त का, सीनेट (ब्रुलीनतान) समान एव प्रमाव का, असेम्प्रती (सोक्षिय जनसमा) स्वतन्त्रता के पिद्धान का प्रतीक है। जब इन तीना सिद्धानों म समावय होता है तमी स्ववस्था एव स्थायित्व सम्प्रव है। सिसेरों पेटिल के अनुसार राजतान के श्रेष्ठितम, प्रलीनतान को ने विद्यन्त स्था देता है। की का ने निव्यन्तन स्था देता है। की का प्रतीक प्रती का विचार को निव्यन्तन स्था देता है। की का निवास का मिद्धानों का स्थाय स्थाय एव स्थायित्व सम्प्रव है। सिसेरों पेटिल के अनुसार राजतान के श्रेष्ठितम, प्रलीनतान को निव्यन्तन स्था देता है। की का स्थाविक प्रता का तता का निवास का स्थाविक प्रता का स्थाविक प्रता के का स्थाविक प्रता के का स्थाविक प्रता के स्थाविक प्रता के का स्थाविक प्रता के का स्थाविक प्रता के स्थाविक स्थाव

आधुनित युग हे प्रारम्भ कासीसी विद्वान जी बोदा सुन्य विचारक है जिसने राज्यों का वर्षीकरण प्रस्तुत विचा है। उसने वर्गीकरण का आधार राज्य ने प्रभुत्व को धारण करने वाकों की सक्या है। जब प्रभुत्तता एक व्यक्ति के हायों में होती है तो उसे एक्त न, जब नागरिकों के बहुमत से कम व्यक्तियों के हायों में होती है तो उसे कुलीनत ज और जब प्रभुत्तता बहुसस्यक व्यक्तियों के हायों में होती है तो उसे कुलीनत ज कोर जब प्रभुत्तता बहुसस्यक व्यक्तियों के हायों में होती है तो उसे लोकत ज कहते हैं।

बोदा ने राजतात्र को तीन वर्गों में विमक्त विषा है—साही या शुद्ध राज-तत्र, निरक्षा राजतात्र एवं अत्याचारी राजतात्र । धाही राजतात्र में बोदा के अनु सार प्रजा स्वेच्छा से राजा के हारा निर्मित नियमों का पालन करती है, शासक ईक्वर एवं प्रकृति के नियमों के अनुसार धासन करता है तथा प्रजा के अधिकार व सम्मत्ति सुरक्षित रहते हैं। बोदा इसे राजतात्र का ओच्डतम रूप मानता है।

िरहुश राजतात्र में राजा प्रजा पर उसी प्रकार शासन करता है जिस प्रकार प्राचीनकाल में कुलिपता दावा पर शासन करता था। जत्याचारो राजतात्र में राजा अध्यक्त के अपर मनमाने बग से शासन करता है तथा वह प्रकृति एवं समाज के कानूनों की अवहेलना करता है। 10

¹⁷ Dunning, W A History of Political Theories (Indian edn., 1966), pp. 117-118

¹⁸ Gettell History of Political Thought, (Hindi version, 1960), p 106

¹⁹ Sabine of cit, p 346

यॉमस हॉन्स (Thomas Hobbes) ने वर्गीनरण म नाई नवीनता वही है। अरस्तू ने वर्गीनरण की तुलना में हा स ना वर्गीनरण पटिया है। अरस्तू नी मीति राज्य के लक्ष्य या उद्देश को हॉन्म महत्व नहीं देता। हा स ने वर्गीनरण का आधार एक, मुख्य या बहुत व्यक्तिया ने हाथों म सप्रमुता ना होना है। हा म के अनुसार मिंद प्रमुत्व ना प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति करता है तो वह राजन ज है। यदि सभी व्यक्तिया की समा ने हाथों में प्रभुत्व है तो उसे सोनय Commonwealth) और यदि समी व्यक्तिया के एक अप ने हाथों म प्रभुत्व है तो उसे कुत्तीनत ज वहने। हॉस अराज्य चारत ज (Tyranny), अल्यत ज (Olgarchy) एव अराजनता नी अवस्था में अपरि-धित नहीं था, लेक्नित वह इन्ह भूयन राज्य ने स्वरूप के रूप म स्वीवार नहीं करता।

जॉन लाक (John Locke) के अनुसार धासा वा स्वरूप इस यात पर निमर करता है कि विधायों ब्रांक किस अग म निहित है। जॉन लाक विधायों ब्रांक को ही प्रमुख मानता था। यदि समाज के बहुसत्यकों द्वारा विधि निर्माण की धांकि मा प्रयोग स्वय विधा जाता है और विधि को अपने द्वारा नियुक्त अधिनारिया से प्रियानित कराया जाता है तो यह खुद्ध लोकत आरम्ब छताता है। यदि विधिनिर्माण की शक्ति समाज के थोड़े के व्यक्तिस्व वस्वा उनके उत्तराधिकारिया के शिधा म है तो वह अल्पत म है। यदि शक्ति के हाथ म है तो वह राजत म है। यदि शक्ति के हाथ म है तो वह राजत म है। यदि शक्ति के हाथ म है तो वह राजत म है। यदि शक्ति के हाथ म है तो वह राजत म है। राजत म, पुत्तीनतन्त्र एवं सौरत म म वर्गीगृत विधा है। राजत म को उत्तरे वसानुमत एवं निवाचित दो वर्गों म विभाजित विधा है।

मोटेस्बयू (Montesquieu) न राज्य को तीन वर्गी म वर्गीकृत किया है गणराज्य (Republic), राजत न (Monarchy), एवं तिरकुरात न (Despotism)। गणत नीय ध्यवस्था के उत्तने दो उपविभाग किये हैं क्षोत्र नीय (Democratic) एवं पूलीनत नीय (Anstocratic)।

मणतात्रीय व्यवस्था में सप्रभुत्व शक्ति सम्यूण व्यक्तिया के निवास में या उनके एक मारा में मिहत होती है। सात्तात्रीय व्यवस्था में एक व्यक्ति स्थापित विधि सं अनुमार सामन करता है। तिन्दुन्तित में एक व्यक्ति किया विधि सा नियम के अनुमार सामन करता है। तिन्दुन्तित में श्रेटक्यू के अनुमार प्रभन नामन के एक विभिन्न निद्धात ते सम्बन्ध है। सावकतिम सेवा (chil hetide) का माय साम सामन ति ति ति सम्बन्ध है। सावकतिम सेवा (chil hetide) का माय साम साम का का साम समान (honour) सावकत्र के एवं अंध (slavishness) तिन्दुन्ति का सामारमूत्र निद्धात है। किया विभाग साम स्थाप के सामन स्थाप स्थापत्र ति निद्धात है। किया है। नियम के स्थापत्र साधकत्र करता मननीय एवं अतस्थीय सरसारों का नेद हो दिस्स के अनुसार साधकत्र करता सामन के स्थापत्र करता साधकत्र विभाग साधकत्र करता साधकत्र साधकत्र करता साधकत्र साधकत्र

²⁰ Montesquieu Stutt of Lavr Book II Ch I Pefet 1. C. II Sabine I Hurry of Poli and Thery, 1957, p =69

फारा की राजनीतिक समस्यामा स प्रभावित होतर अका वर्गीतरण का कवल करपना पर आधारित विया है। ¹

रसो ने राज्या को राजवान, बूलीनत न एव लोकतान में वर्गीहत निया है। युलीनतन्त्र को उसके द्वारा प्राष्ट्रतिम (natural), निर्वाचित (elective) एव बनानु गत (hereditary) में वर्गीवृत विया है। रसी प्रत्यक्ष प्रजात त्र ना समधन था।

जमन विचारन ब्लूटक्सी (Bluntschli) ?? ने बरस्तू ने वर्गीनरण नो स्वीनार क्या है। कि तु वह उसमें घमतात्र या देवतात्र (Theocracy) के एक और दम की यढा देता है । देवतात्र भा पतित रूप मूर्तिसात्र (Idolocracy) है । ब्लूट्स्ली ने अनुसार देवतात्र मे विसी मानबीय सत्ता को स्वीकार नही किया जाता, अपितु सर्वोच्च सत्ता ईश्वर या निसी देवता (God) या निसी अन्य देवपुरुप या प्रत्यय (Idea) मे निहित होती है। शासक वन सप्रभूता को घारण नहीं बरते अपित वे अहरय सत्ता के सेवक या उपाधिकारी (Viceregent) होते हैं । यूरोप में मध्य युग में पोप का शासन इसका एक उदाहरण है। इल्टब्ली के वर्गीकरण की मानर ने अवैज्ञानिक प्र लीकॉक वर्ग ने भ्रामक बताया है।

19 दी सदी वे जमन विचारक रॉबट बान मोल (Robert Von Mohl) ने राज्यो को पितृसत्तात्मन (Patriarchal), घमत त्र (Theocratic), निरम्शत त्र (Despotic), प्राचीन राज्य (Classic), साम ती (Feudal) एव सर्वैद्यानिक (Consti tutional) बगों मे विभाजित किया है। बान मोल के वर्गीकरण 5 का आधार ऐति

हासिक है।

. इसका सबसे बडा दोप यह है कि शासन के विभिन्न वग एक दूसरे का अति-क्सण करते हैं। इसमे राज्य व सरकार के बीच भेद करने का प्रयत्न भी नहीं किया गया है। गानर के अनुसार यह किसी वधानिक आधार पर आधारित नहों है और न ही इसका व्यावहारिक मूल्य है।²⁶

सरियद का वर्गीकरण वतमान लेखको मे सर जे ए आर मरियट का वर्गीकरण ⁷ उसके समय तक के सभी वर्गीकरणी मे श्रेष्ठ माना जाता है। उसने आधुनिक राज्यो का निम्नांलखित तीन पथक आधारी पर वर्गीकरण किया है

(1) क्या राज्य एकात्मक है या संघात्मक ?

23 24

Garner op cit p 230

Marriot J A R English Political Institutions, (Fourth edn., 1955), pp 15 25

Sabine Ibid, p 469
Bluntschli Theory of the State, Book VI quoted by Garner op 21 22

Bilittescrit theory of the States, DOOR VI quotest by Sacratic of the p. 230 31 Garner Political Science (1951) p. 231 Garner Political Sciences, 1929 p. 114 Von Mohl Encyclopéala of Political Sciences, Sec. 15. 43. 44, 47, 48, 50 cited by Garner of cit., p. 230 25 26

(2) वया राज्य वा सर्विधाा दुष्परिवतनीय (rigid) है या मुपरिवतनीय राज्यो एव सविद्याना वा वर्गीवरण | 25 (flexible) ?

(3) नया सासन ना स्वरंप संसदीय (parliamentary) अर्थात उत्तरदायी है या अससदीय (non parliamentary) अर्थात राजत त्रीय (monarchial) या अध्यक्षात्मन (presidential) है ?

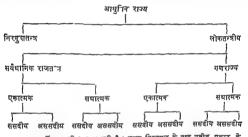
एनात्मन एव सपात्मन ना अन्तर यक्तिया वे विमाजन (division of power) पर आपारित है। दुष्परिकतनीय एव मुपरिकतनीय वर्गोकरण सविधान म विवादन की प्रवाली पर जापारित हैं। तीवरे वर्गीवरण वा आधार वायपालिका एव यवस्यापिका हे पारत्यरित सम्य च हूँ । नायपानिका यि व्यवस्थापिका हे प्रति जनर ही समा हो जाती है। जहाँ वायपातिका एव व्यवस्थापिका एक दूबरे से स्वत व और पुषक होते हैं अर्थात सामन के अग्र के पारस्परिक सम्य सिंक पुष्वककरण पर आमा-देश हाथ ह जराव भावत । ज्यान भावता । भावता के ज्यात देशकारण पर आधार दित होते हैं जसे अध्यक्षात्मक प्रणाली कहते हैं। राजत न से एक व्यक्ति का सासन होता है परतु वह वशानुगत आधार पर नियुक्त होता है। फास एकाराव राज्य और पत्रक प्रवास्त्र प्रवास्त्र प्रवास्त्र प्रवास्त्र प्रवास्त्र सिवधान मुगरिवतनीय सामिले हैं। वार्षभार प्रणाह का बनाव का स्वतंत्र व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्य क्षराताम् व्यवस्या है उदाहरण हैं। अफगानिस्तान्त्र एवं नेपाल म राजत न है। इगलैण्ड में समसीय ब्यवस्था होते हुए भी वहाँ सर्वेवानिक राजत न है।

अमेरिका म राष्ट्रवृति है। मारत म भी राष्ट्रवृति है पर तु उसकी स्थिति बिटिश राजा के समकक्ष है। ससदीय स्वतस्या म दो कामणातिकार्—नाममात्र की एव बात्तविक होती है। नाममात्र नी नामपातिका राज्याध्यक्ष ना काय सम्पादित पुत्र वारावकः हार्ग है। अभिन्या है। अभिन्या है। समस्ति राष्ट्रपति जो अध्याक्षास्मक नामपातिका है। राज्य न सासन दोनो का ही अध्यक्ष होता है। स्टोफेन लीकाक का वर्गीकरण

भो० स्टोक्न लीवांक ^१ में पियट से मिलता जुलता पर तु जससे कही व्यापक बर्गीकरण प्रस्तुत किया है। उसने बाधुनिक राज्यों को मोटे तौर पर दो वर्गों म विमा-जित हिया है — निरुष्ट्रस (Despote) एवं लोकत नीय (Democratic) । नार त नीय राज्यों के उसने दो मेद किये हैं—सर्वमानिक राजत म एवं मणराज्या स्वयानिक राजत में प्रमुखता जनता में निवास करती हैं। बशानुगत बाधार पर राज्य वा अध्यक्ष होते पर भी राजा नाममान का शासक होता है। उसकी सक्तियों का प्रयोग बाल्बर हो। १६ मा राजा पानमान रा चावत हो। हा ठ०४। चारावा पा अपार अय तोकतंत्रीय संस्थाको हारा किया जाता है। संस्थानिक राजतंत्र में द्रश्लेण्ड सर्वोत्तम ज्वाहरण है। गणराज्य म राज्य का अध्यक्ष जनता द्वारा निश्चित कास ने

हफामिताल में दुवाई 1973 ने क्रांति होरा राजवचीय स्वस्था ना अंत कर दिवा है और गंपराज्य को स्थापना को धीयमा को गंधी हैं। I nacook Stephan Premarke of Political Science 1020 v. 117 29 Eacock, Stephen Elements of Political Science, 1929, p. 117

लिए चुना जाता है। उपरोक्त दोना प्रवार ने पुत्र दा मेर तिये गये हैं—एकासमर एवं संपादनक । एकारमन एवं संपादनक प्रत्येत को तुत्र संसदीय एवं असावीय वर्णों में विमाजित विया गया है। विजयाहरू ने लीकाक वे वर्णीकरण को निम्त तालिका द्वारा व्यक्त विया है



यह वर्गीकरण भी व्यापक नहीं है। प्रथम विश्वपुद्ध के बाद नवीन प्रकार के राज्यो का यूरोप मे उदय हुआ । यह सर्वाधिकारवादी राज्य लोकत न विरोधी सिद्धा त पर आधारित थे। इटली का फासी गदी शासन, जमनी का नाजीवादी शासन एव रूप में साम्यवादी सरवारे इस प्रकार के राज्यों के उदाहरण है । जमनी एवं रूस गणत त्रीय देश थे तथा इटली मे राजत त्र था । सभी मे एकदलीय प्रणाली थी। इन देशों में कायपालिका उत्तरदायित्व के सिद्धात पर गठित नहीं थी । व्यक्ति का अस्तिस्व राज्य मे विलीन हो जाता है। राज्य का अध्यक्ष अधिनायक या अधिनायक की तरह का होता है। वह सम्प्रण समाज के जीवन को नियमित एव निर्देशित करता है। इत राज्यों में व्यक्ति की स्वत त्रता का निषेध होता है और व्यक्तियों को लोक सात्रीय देशों की भाति मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। प्रो॰ लीकाक के वर्गी करण म इन राज्यो का उल्लेख नही है। इन राज्यो नो वर्गीकरण मे शामिल करने में लिए यह आवश्यक है कि आविनिक राज्यों में निरक्शत त्रीय एवं लोकत त्रीय वर्गों के अतिरिक्त एक तीसरा वम और जोड़ा जाय जिससे अलोकत श्रीय राज्यों को स्थान दिया जा सके। लेकिन इस वर्गीकरण म भी एक दोप रह जाता है। लोकत त्रीय शासन मे दो रूप हैं-प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष । प्राचीत यूनान मे नगर राज्या का सगठन प्रत्यक्ष लोकतत्र के आधार पर या। आज प्राय सभी लोकतत्त्रीय देशो मे अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधिमुलक लोकतत्र पाया जाता है। अव व्यावहारिक इंब्टि से लोकतत्रीय मरकारों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष में विमाजित न करने से कोई हामि नहीं है। प्रत्यक्ष लोकत न आधुनिक काल में कवल ऐतिहासिक महत्व रखता है।

सी एक स्ट्राग का वर्गीकरण

r

ī

बाधुनिक राज्यों के वर्गीनरण ने तिए स्ट्राम न अनुसार एस आधार ढढ़ने की बावस्यकता है जो सभी राज्या भ पायं जाते ही तथा जिनसे राज्यों को उनके सगठन नी विभिन्ता के बनुसार वर्गीहत किया जा सबे । इसरे सन्दी में, प्रतीक भाषार सा ना प्यान्त्रणा में अर्थार प्रभाटण । या जा एवं । प्रवर पट्या या ज्ञानार था र्वेषता की जीच करने राज्यों की उनने भेद के अनुहम निम्न वर्गों में वर्गीहत कर देना चाहिए । स्ट्राम के अनुसार क्योंकरण के पान आधार है अ (1) राज्य की भवृति अर्थात एकात्मक या समात्मक ।

- (2) सविधान की प्रकृति अयति दुष्परिवतनीय या सुपरिवतनीय । (3) व्यवस्थापिका की प्रकृति।
- (4) मायपालिका की प्रहति।
- (5) यायपालिका की प्रकृति।

स्ट्राम ने जयबुक्त वर्गोकरण को स्वष्ट करने के तिए निम्नतिबित वातिका

न्त्रित की है 31 किए वर्गाकरण को
विभाजन या वर्गोकरण के आग्रम
भ विष्
के वर्गाकरण
के आधार
1 राज्य न
1 राज्य की प्रकृति एक्ट्रा
्राह्मीत । एक ।
2 सिकार १
11419 27 1
2 संविधान की प्रकृति सुपरिवतनीय (आवृत्यक मही के असिखित को)
जिल्लामा ।
वें अक्रिक्ट (अविरयक्त्रक) अवस्थात्मक
महति भी (1) (म) ब्यस्क मताधिकार (धा वत्यक लिखित हो)
विविध्यक्त (वीवव्यक्त
रेपति समाध्या रेपति लिख्य
मकृति (1) (व) ब्यस्क मताधिकार (वानस्पर्क सेही कि पूर्णत सिस्तित हो)
(व) एवसदस्यीय निर्वाचन (१) (व) सीमित वयस्व क्षेत्र (व) (व) स्वाधिकार
्रे विद्याय विक्र मितरिं समित
्रिक्षेत्र ग्विनिन् विश्वासकार विश्वस्क
(1) अनिर्वाचित द्वितीय (व) व्यवस्थिय निर्वाचन सदम
मानाचत कि किय क्षेत्र
सदन दितीय सिन कर्पाय निर्वाचन
पदन व्याप (n) निर्वाचित या आशिव स्प मे निर्वाचित या आशिव स्पन महोत
4 कायपालिका की प्रत्यक्ष लोक नियं त्रण सदन विविधिय
5 महात भी ससदीय (111) इस प्रकार
वायपातिक विकास विकास के कि
प्रमृति की सम्बोध प्राथमातिका की विकि 2 प्रमृति विकि 2
प्रहृति भाग की विधि के पासन के बाधीन विधान के बाधीन प्रभावक के के के किया कि किया के बाधीन प्रभावक के किया के किया के किया किया किया किया किया किया किया किया
(क्रासन के अपन
विभाग हिंद अधिन
(धामा य विधि वाले प्रशासकीय विधि -
Offone C
्रिंभाग विद्य स्थाति प्रशासकीय विद्य का कि । प्रशासकीय विद्य का भीन
lbid, p 77 % cut, (1963), pp 62 63
(1-03), PD 63 ca
02 63

उपर्युक्त वर्गीवरण रे आधारा का विलक्ष्यण निम्नवत् है राज्य की प्रकृति का आधार शक्ति का विभाजन है अर्थात् राज्य एकात्मक है

अथवा सपारमन । सिवधानो ना विमाजन उननी सद्योधन प्रतिया पर आधारित है। लिखित एव अलिखित मे सविधानो ना वर्गीनरण आमन है। सद्योधन प्रतिया के अनुसार सविधान सुपरिवर्तनीय एव दुष्परिवर्तनीय मे वर्गीकृत विये जाते हैं। उपरोक्त

ाताबत एम आलावत न सावधाना वा चनाव एए आमव हा सशाधन प्राप्तन प्राप्तिया क अनुसार सविधान सुपरिवत्तनीय एव दुष्परिवर्तनीय मे वर्गीकृत विये जाते हैं। उपरोक्त दोनों बर्गीक्रण के उपयुक्त आधार हैं। ^{हो} व्यवस्थापिका की प्रकृति के सम्बन्ध मे स्ट्राग का मत है कि आधुनिक व्यव-

स्पापिकाओं को एनवस्तीय एव डिसदनीय व्यवस्वापिया में विमाणित करता उपयोगी आधार गृही माना जा सकता। पूजीलैण्ड, डेनमान आदि देशों में एनसदनीय स्ववस्वापिया में विमाणित करता उपयोगी आधार गृही माना जा सकता। पूजीलैण्ड, डेनमान आदि देशों में एनसदनीय स्ववस्वापिया है। वे इस व्यवस्था हारा अपनी सम्पूण आवस्यन्ताओं भी पूर्ति कर नेते हैं जविक कुछ देशों में सचीय व्यवस्था ने नारण डिसदनीय व्यवस्थापियाएँ स्थाविसे हैं । स्ट्राग ने व्यवस्थापिया नो वर्गीवृत करने ने तीन आधार प्रस्तुत विसे हैं

 सतदान प्रणासी-—इस सम्बंध म निर्वाचन एवं क्षेत्र सम्बंधी दो प्रश्न विचारणीय हैं।

(2) व्यवस्थापिका या विधानमण्डल के द्वितीय सदन की प्रकृति—द्वितीय सदन को निर्वाचित (आधित रूप से निर्वाचित) तथा अनिर्वाचित के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। यह केवल द्वित्यत्नीय व्यवस्थापिकाओं के सादम में ही सम्मव है।

सम्मव है।
(3) वृक्ष आधुनिक सविधानो से व्यवस्थापिकाओ पर मतदाताओ की प्रत्यक्ष लोक नियत्रण की शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं लेकिन यह व्यवस्था यहुत से सविधाना मे

त्ताक । तम प्रण पर चाराव्या अपाय का पाया है चाकण यह ज्यवस्था बहुत स सावयाना स नहीं हैं। कायपालिया को उसकी प्रकृति की दृष्टि से संसदीय एवं अससदीय में वर्गीकृत

कावपालना ना उराका अञ्चात का द्दान्ट च चलराय एव अससराय म बगाइत क्षिया गया है। ³⁴ स्यायपालिका की प्रकृति के बनुसार वर्षीकरण का आधार विधि का शासन (Rule of Law) एव प्रशासकीय विधि (Droit Administratif) है। ³

प्रत्येक राज्य का उपयुक्त बाघारो पर परीक्षण करने पर उनके अलग-अलग परिणाम होंगे। एक राज्य एक ही प्रकार का नहीं होगा। यदि एक राज्य एकात्मक हो सक्ता है तो उसवा सविधान स्वीला न होकर कठोर भी हो सकता है। स्ट्राम ने उपर्युक्त तालिला ने बाघार पर इनकेंग्ड और अमेरिका के सविधानो को वर्गाहत विमा है।

अध्ययन की सुविधा हेतु इसे निम्नलिखित तालिका द्वारा व्यक्त कर सकते हैं

³² देखिए छटा अध्याय

³³ देखिए तीसरा अध्याय ।
34 देखिए नवी अध्याय ।

³⁵ देखिए पद्भवां अध्याय।

आघार	इगलण्ड का सविधान	सयुक्त राज्य अमेरिका का सविधान
1 राज्य की प्रकृति	एकात्मक	संघारमक
2 सविधान की प्रकृ		कठोर
3 व्यवस्थापिका की प्रकृति	(1) (व) सावभीम वयस्क मताधिकार	सावभीम वयस्य मताधिकार
	(व) एकसदस्यीय निर्वा चन-क्षेत्र	एक्सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र
	(11) अनिर्वाचित द्विसदनीय व्यवस्थापिका (वशानुगत)	निर्वाचित द्विसदनीय व्य- बस्यापिका
	(m) कोई प्रत्यक्ष लाक निय-	काई लोक नियापण नहीं
4 कायपालिका वं प्रकृति	ससदीय े	अससदीय (अन्त्र्यक्षात्मरः)
5 यायपालिका क प्रकृति	विधि का शासन	विधि का शासन

स्ट्राग के अनुसार उपयुक्त वर्गीवरण विभिन्न आधुनिक सविधान गारित्रया द्वारा प्रस्तुत सुमावो पर आधारित है। लेकिन किसी ने भी अपने सुभावो को भिया-वित नहीं किया था। ³⁷ स्ट्राग यह दावा नहीं करता कि यह वर्गीकरण पूण है क्योंकि वर्गमान सबैधानिक राजनीति को तुलनात्यक होट्ट से वर्गीकृत करना कठिन है लेकिन उसका मत है कि यह वर्गीकरण पर्याप्त ब्यापक है।

कॉ॰ आर्चीवादम ने ब्राइस, जेंबस (Jenks) एव मैरियट द्वारा प्रस्तावित विचारों में आधार पर सासन ने वर्गीवरण की एव तालिका प्रस्तुत की है। यह वर्गीवरण दो प्रमुख विचारा पर आधारित है ³⁰ (1) राज्य का काय-दोत्र, एव (2) राजनीतिक संगठन की प्रकृति।

उपर्युक्त विभाजन के दोनो आधारो पर राज्यो को उदार एव सर्वाधियारवादो (साम्यवादो एव क्षांनीवादो) म विभाजित विमा गया है। राजनीतित सारतन की मृद्धित के छ उपमाग किये गये हैं, अधान् राज्य, सविधान, निर्वाचक्य, ध्यवस्थापिका, वायावीता, एव "यायपानिका की प्रदृति । को आपीवादेश द्वारा प्रम्तुन दिचार हुए। द्वारा प्रम्तुन दिचार हुए। द्वारा स्वीकृत वर्षोप राज्यादित है।

बापुनित काल म राजत त्रीय एव ब्रुगीनन त्रीय गामग-व्यवस्थाएँ प्राय समाज हो पुत्री हैं। राजतात्र भी अब मर्वधानित राजतात्रा म परिवन्तित हा मये हैं। इमने कुछ ही अपवाद हैं। अधिनात देगों में लोकतात्रात्मक शामन-व्यवस्था प्रचित्ति है। यदमात मुग लोकतात्र का सुग है। कुछ राज्या म अधिनायकतात्र में विजिल का भी पाये जात है। आगामी पूट्य में माकतात्र का विक्तेपत प्रस्तुत है।

³⁷ Strong of cit, p 63

³⁸ Asirvatham of cit, 1965 pp 347 345



सस्यको ने हाथों में होता है नयोंकि जिस समाज के लोग एकमत नहीं होते उसमें सम्पण समाज की इच्छा का वैध एव शातिमय तरीको से पता लगाने का कोई उपाय नहीं तिया जा सवा है।"¹⁶

उपर्यंक्त सभी परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि लोकत न जनता का या उसवे बहुसरयव माग का शासन है पर त न तो जनता और न उसका बहुसरयक वग शासन करता है। वास्तव में, जनता की तरफ से या जनता का समयन प्राप्त शासन लोकतात्र है। मैकाइवर की परिमाणा में यह भाव या विचार स्पष्ट है "लोकतात्र बहसस्यको द्वारा अथवा अय विसी प्रकार से शासन करने की प्रणाली है। मुलत लोक्स न यह निषय करने का तरीका है कि शासन कीन करेगा और शासन का जरेडव क्या होता ।"¹⁴⁷ लास्की के विचार भी कुछ कुछ इसी से मिलते हैं। उनके अनु-सार "लोकत त्र शासन वा वह रूप है जिसने अन्तगत मनुष्या को उस शामन के निर्माण का अवसर मिलता है जिसके आधीन उन्हें रहना पडता है तथा शासन दारा निर्मित विधिया सब पर समान रूप से लाग होती है।"48

बुछ विद्वान लोशतात्र को शासन के स्वरूप के अतिरिक्त उसे कुछ अधिक और आगे माउते हैं। लोकतात्र न केवल बासन तात्र ही है अपित राज्य व समाज पा स्वरूप भी है। लोकतात्रीय शासन में लोकतात्रीय राज्य निहित है लेकिन यह आवश्यन नहीं है कि लोकत नीय राज्य का शासन अनियार्यत लोकत नीय ही हा । लोकत नीय राज्य किसी भी शासन से सगति रख सकता है। सर्वोच्च सत्ता लोकतात्रीय राज्य मे एक' अधिनायक को प्रदान की जा सकती है जैसे कि सकटकान मे अमेरिकी राप्टपति को क्यापक शक्तिया प्रदान कर दी जाती हैं। अधिताता ने लिखा है कि 'लोकतात शासन व्यवस्था का एक स्वरूप मान नहीं है सोकतात्र म दो बस्तुएँ हैं जो तक की हिन्द से आयो याश्रित हैं तथा व्यवहार में भी अधिक महत्वपूण हैं। वे वस्तुएँ हैं राज्य का विशेष स्वरूप एवं समाज का स्वरूप ।" बास के अनुसार "लोकतात्रवाद में समाज का एक विशिष्ट रूप भी सिनिहित है।" कमारी फालेट ने "लोकत त्रवाद को एक आध्यारिमव बादश माना है।"

अत लोकत त्र सकीण अय मे केवल एक शासन पद्धति है। पर तू अपने व्यापक अय में वह समाज वा सिद्धात एवं जीवन-आदश है। मैंबसी व बासार "यह ऐसी जीवन पद्धति की खोज है जिसमे व्यक्ति की इच्छा एव त्रियाओं को विना किसी दबाब के ही समिवत विया जा सबे । एसा माना जाता है कि सम्प्रण मानवता के लिए ऐसा ही जीवन श्रेष्ठ है नयोकि मानव एव सृष्टि की प्रकृति के यह मवधा अनुकृत है।"

⁴⁶ Bryce Modern Democracies Vol I (1921) p 23 quoted by Coker,

MacIver The Web of Government, p 198
Laski Liberty in the Modern State, (1961), p 56

Assrvatham Political Theory 1965 p 453 Maxey Political Philosophies, 1959, p 690 50

लोकता िनक सामाजिक न्यवस्था में ममानता एव भ्रानुत्व सामाजिक जीवन के आधार होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि लोकता िनक समाज में लोकत नीय शासन एव राज्य मी हो। मुमलिम समाज अत्यधिक लोकता िनक है लेकिन वे लोकत त्रीय शासन व्यवस्था एव राज्य ने स्वीकार नहीं वरते। पाकिस्तान एक इस्लामी गणत न है। इसने विपरीत, अमेरिना में लोकत नीय शासन होते हुए भी लोकत त्रीय समाज नहीं है। यहा समाज में गरीव व अमीर को असमानताएँ है और काले व गोरेना भेद उग्र खर्म विषयान है।

लोकतान जीवन के प्रति एक विशेष हस्टिकोण है। इस रूप में जीवन ने प्रति होकतानीय हस्टिकोण विनय सुविधा, समता, सहिष्णुता, मानवीय व्यक्तित्व के प्रति सम्मान आदि गुणों को महत्व देता है। अन्त में, लोकतान को एक आज्यारिमक शक्ति में रूप में भी स्वीकार किया गया है। लोकतान को धार्मिक सिद्धा तो की सी मा यता प्राप्त है।

लोकतात्र का सक्षिप्त इतिहास

प्राचीन चीन व सारतवप में सवप्रयम स्वशासित नगर-राज्यों का उदय हुआ था। प्राचीन चारत में स्वशासित गणराज्यों का स्पष्ट उरलेख मिलता है। लेकिन लीवता ने स्पष्ट स्वरूप के विकास का श्रेय यूनानियों को ही प्राप्त है। यूनान के लोकता ने सप्ट स्वरूप के विकास का श्रेय यूनानियों को ही प्राजनैतिक अधिकार प्राप्त में में विकास स्वरूप के निविद्या पार्च नहीं थे। हैरेनसा के अधिकार प्राप्त नहीं थे। हैरेनसा के अधिकार प्राप्त सही थे। हैरेनसा के अधिकार प्राप्त नहीं थे। हैरेनसा के अधिकार अधिकार अधिकार प्राप्त नहीं थे। हैरेनसा के अधिकार अधिकार थे।

- (1) यूनानी लोकतात्र का स्वरूप प्रत्यक्ष या । उसका स्वरूप आधुनिक लोक सात्र की तरह अप्रत्यक्ष नहीं था ।
- (2) पूनानी लोकतत्त्र वासता एव श्वीपण पर आधारित या न कि आधुनिक प्रमुख तीन मिद्धाता—स्वतत्त्रता, समानता एव श्रातृत्व—पर ।
- (3) पूनान म लोक्तात्र नगर-राज्यो तक सीमित या अत राप्ट्रीयता का सिदात वहां माय नही था।
- (4) यूनान में लोनतात्र बग-समय में रत या । वह निधमो द्वारा घनिको की सम्पत्ति में अपहरण के लिए सुटरो का समठन या 1⁸ प्लेटो इसी यूनानी लोकतात्र का विरोधी था ।

रोम म कभी भावतात्र नहीं रहा था। वहीं गणतात्र-काल में भी भीवतात्र नहीं था। रोम म दागना की प्रधा कामम रही थी। नागनिक वेबल औपचारिक रीति में ही राज्य-नाथ म भाग लिया करते थे। वास्तव में रोम का गणराज्य अभिजार्य ताजीय था।

मध्य-पुग म नाम नी ध्यवस्था का जोर या पर तु मध्य-युग म ही प्रतिनिधित्व

⁵¹ Hearnshaw Democracy at the Grossways, p. 89

की धारणा ना जम हुआ था। इससे अप्रत्यक्ष लोकतान ने विकास के लिए माग प्रदास्त हो गया। सविदा सिद्धात का विकास हो चुना था। साम तवाद विने द्री करण एव परस्पर सविदा या समकीते के सिद्धातो पर आधारित है। उस गुग मे ने द्रीय सत्ता का विवास सम्मव ही नहीं था। धार्मिन क्षेत्रों में चल एव चल की अन्य प्रवासकारी समितियों की रचना हुई । आधिन क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में प्रात्व सस्याओं एव दला की स्थापना तथा छोटे-छोटे ग्राम सगठना, व्यापारिक नगरो एव राष्ट्रीय राज्या के विवास ने प्रजात त्रीय रूप का बहुत कुछ कायम रखा था।

मुचार आरोलन ने राजनीतक लोकत प्रवाद के सिद्धात निश्चित किये थे तथा लोकत प्र के वतमान स्वरूप ने निर्माण एव विकास में आधुनिक युग की चार क्रातियों से सहायता मिली हैं

- (1) 1688 ई॰ की डगलण्ड की रक्तहीन काति ने ब्रिटिश ससद की सर्वोच्चता स्थापित की।
- (2) अमेरिकी स्वात ज्य सम्राम के फलस्वरूप अमेरिका के 13 ब्रिटिश उप-निवेदों ने अपने को स्वत न घोषित कर दिया तथा मो टेस्क्यू एव लॉक के व्यक्तिगत स्वत नता के सिद्धाता को अपनाया ।
- (3) फ्राम की राज्यकाति (1789 ६०) ने समानता,स्वत त्रता एव आतृत्व के सिद्धातों की स्थापना की ।
- (4) औद्योगिक काति ने आधुनिक पूजीवाद की समस्त रूपरेखा को स्थिर करके सोकत क की इडतापूकक स्थापना की।

लोकतात्र का वर्गीकरण

लोकतात्र के निम्न दो मुख्य वर्गीकरण किये जाते हैं

- (1) प्रत्यक्ष (शुद्ध) एव अप्रत्यक्ष (प्रतिनिषिमूलक) प्रजात त्र [Direct (Pure) and Indirect (Representative) Democracy] ।
- (2) सबैधानिक राजतात्र एव गणतात्र (Constitutional Monarchy and Republic) ।
- (1) प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लोकत त्र—प्रत्यक्ष लोकता त्र में जनता स्वय प्रत्यक्ष रूप से सावजिनक मामलो में अपना मत प्रवट करती है। प्रत्यक्ष प्रजात त्र पूनान के नगर राज्यों में प्रचित्त था। सभी स्वत त्र पूनानं नगर समा में एकिंतित होते, विधि करा निर्माण नरते शासकीय अधिकारियों की नियुक्ति करते, राजदूतों का स्वागत वरते एव स्वय त्राय करते थे। मध्य युग में इटली के नगर-राज्या मं भी ऐसी ही व्यवस्था थी। स्विटलपर्तण्ड के नेण्टना मं भी प्रत्यक्ष प्रवात त्र में व्यवस्था थी। व्यवस्था थी। स्वटलपर्तण्ड के नेण्टना मं भी प्रत्यक्ष प्रवात त्र में व्यवस्था थी नो अब तन चली

रही है। रूमो प्रत्यक्ष प्रजात न का तीन्न समयक था। लेकिन प्रत्यक्ष प्रजात न छोटे राज्यों में ही सफल हो सकते हैं जिनमें कि राजनीतिक मामलो पर विचार-विनिग्य हेतु सरलतापूषक एकत्रित होने की सुविचा हो। इसके अतिरिक्त, समाज मे पर्याप्त समानता एवं सम्पन्ता होनी चाहिए तथा लोगों के पास सावजनिक कार्यों के लिए पर्याप्त समय भी होना चाहिए।

आधुनिक विचाल एव वही जनसख्या वाले देशों में प्रत्यक्षप्रजात न सम्भव नहीं है अतएव प्रतिनिधि लोकत न का विकास हुआ है। जनता हर नवीन निर्वापन म अपने प्रतिनिधियों नो चुन कर उन्हें कुछ वर्षों के लिए शासन-काय सीप देती है। प्रत्यक्ष लाकत न तो अब स्विटजरलैण्ड एव कुछ अमेरिकी राज्यों में जनमत समह (Referendum), उपत्रम (Inttative) एव प्रत्याह्मान (Recall) के रूप में ही धैय है। प्रतिनिधि लोकत न से सैदानित रूप में राज्य की शास्त्र सम्मूण जनता के हायों म होती है। उसना प्रयोग जनता का वापने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। बतमान समय म समस्त राज्या में प्रतिनिधि लोकत न है। प्रतिनिधिमूनक प्रजात न वे दो प्रापा कर अध्यक्षात्मक एव सवदीय लोकत न हैं।

(2) सबैधानिक राजतात्र एव वणराज्य—सवधानिक राजतात्र में राज्य या अध्यक्ष वनानुगत होता है। जदाहरण के लिए, इस्लैण्ड के राजा की शक्ति नाम मात्र भी है। वह राज्य का प्रमुख है शासन का नहीं। शासन की शक्ति मिनगण्डल म निहित है। मिननण्डल वास्तविक शासन होता है। मिननण्डल राजा के प्रति जस्ति होतर ससद—जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियो—के प्रति जसरदायी होता है।

61.11 6 1

गणतात्र वह शामन-भडति है जिसमे राज्य का अध्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित होता है। मारत, फान्स एव संयुक्त राज्य अमेरिका गणतात्र के उदाहरण हैं। स्रोकत त्र के मुल सिद्धान

लोगत म ने विकास में साथ-साथ विशत दो तीन हजार वर्षों में उसके निम्न युनियादी तिद्धां ता वा विकास हुआ है

- (1) सायभीम मुख का सिद्धात । सोनतात्र में सभी समयग यह मानते हैं जिस्ता जीवा का अतिम उद्देग्य है।
 - (2) व्यक्ति माध्य और शेष समस्त वस्तुर्णे साधन मात्र हैं।
- (3) स्पत्ति की गरिमा अर्था मनुष्य का व्यक्तिस्य पवित एव गरमानि है। मनुष्य स्वमायत्र अरूप्र है और उसम निवेक, बुद्धि एयं नैतिका की स्वामाविक भवता है।
 - (4) मभारता एवं स्वयालया व गिद्धातः।
 - (5) अन्त प्रत्या का सिद्धान अयात् जाताप्राहे । साराप्त का सहसिद्धान

राज्यो एव सविधानो वा वर्गीकरण | 35

है कि समाज की सामूहिक शक्ति मम्पूष समाज में निहित है, किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह म नहीं । यहीं लोन त्रमुख का सिद्धा त कहा जाता है । त्यावहारित हॉटि से लोकतात्र की प्रमुख विशेषताएँ निम्नवत् हैं—

(2) व्यस्न मताधिकार की व्यवस्था होनी चाहिए।

FT 1

(3) विधानमण्डल निरिचत नाल के लिए चुना जाना चाहिए। अध्यक्षात्मक देशों म राष्ट्रपति निहिचत काल के लिए चुना जाना चाहिए, न कि जीवन मर के लिए। (4) प्रत्यव नागरिक को निर्वाचन म खडे होने एव योग्यतानुसार बातकीय पद प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए।

(5) वासन को सर्वयानिक तरीने से निर्वाचन हारा बदलने का अधिनार होना चाहिए, हिंसा हारा परिवतन अवाधनीय है। राजनतिक दला के निर्माण एव शासन की नीतियों की आलोचना का अधिकार होना चाहिए अर्थात विचार एवं अमि व्यक्ति वी पूण स्वतं नता होनी चाहिए। लोकत न का समयन

प्राचीन बात में खरस्तू और आयुनिक काल में जॉन लाक से लेकर अने---विद्वानों ने लावत त्र का समयन निम्न आधारों पर किया है— (1) अरस्तु वा मत या कि एकतन व अल्पतन से लोकतन श्रेट धासन है, क्योंकि बहुत से व्यक्तियों की बुद्धि एवं अनुसब क्य लीया की अपसा अधिक हीता है चाहे वे पोडे से व्यक्ति बुढि में मितने ही शेष्ठ क्यों न हो। इसके अंतिरिक्त,

शासन म माग तेने स नोगो म सम्मान की मावना उत्पन्न होती है। शासन से बिवत होने पर व्यक्ति अपमानित अनुमन कर सकता है। फलस्वरूप अस तोय फैल सकता है भीर काति का कारण बन सकता है। 52 तत्ता (Soltau) के अनुवार सावन त के बार अनिवास साधार है—(१) विकास एव

हनता (Soltau) के जन्नवार नाहर न के बार अनिवाय जाभार है—(१) विश्वास एक की एरता र तो आवश्यक है और न शान्तीय। (२) निरोण प्रवानीतिक हिन्ता एक उपहार काम के १६ (१) राजनीतिक जीवरार तथी थे। विज्ञा के एक प्रवानीतिक हिन्ता एक का वर्षाम । Refer to As Intelled to 10 Polling के कमान के एएए।, जम, का वर्षो में भीरिया के ने मान के भारत होने चाहिए। 10 Milliograe कमान के प्रवान एक उपहार ने भीरता के ने मान के भारत होने चाहिए। 10 Milliograe कमान के प्रवान एक कमान के भारत के भा पत्र (वापनाधवा (बावत ब्यूवरंभा का अ त ((८) मानव का मुक्ता मावकाखा (३) समान का मार्थ मार्थ का मार्य का मार्थ का मार्थ का मार्थ का मार्य का मार्य का मार्य का मार्य का मार्थ का मार्य का मार्य का मार्य का मार्य का मार्य का मार्य क वाभा क्षा वा बाह्या दोना 'चाह्य ((4) वामानंव नात क प्राना पर जनवा होरा निवस । (5) बहातीन, म मि दिया होरा मामानिक परिवसन । Refer to Political Throns in Recent Times Pp 199 200

[ा] Maccast Louis pp 1575 200 जैकेड (C.P.M. Joad) ने लोगच व है लिए जिस्स सामग्रह विदालों गा स्लोच हिंगा 53 भीड (U.L.M. Joan) न नामत त न अन्य नमन बावश्यन विद्याला मा जन्मत अन्य अन्य क्षेत्र के विद्याल मा जन्मत अन्य अन्य है—[1] पाक बाध्य वय राज्य वापन हुँ । (2) पाकरल के विकास व निष् वावस्वर वामाजिक परिस्थितियों का निमाण होना चाहिए । (3) बनवा के प्रविनिधि ही बासन के वीमाजिक परिस्थातम व जिनान होना चाहिए। (३) वनता क आवागाव हा चावन व स्वस्य एव रोज्य को विधिया के बारे स कवित निषय बरें। (४) विचार एव विधिया के विधिया के विधिया के विधिया के विधिया रवहरू एव राज्य का विशेषा के बाद के कान्यत विशेषा करें। (१) विश्वार एवं कान पात रा रवनन्त्रता तथा विरोधी देती के निर्माण की स्वतन्त्रता होनी विहिंह। (३) सभी विस्तित्र स्वान्ता वया विधान क्षा क्षांचान का स्वतंत्रता होना साहर । अ वस्त साहर । श्री वस्त साहर । श्री वस्त साहर होने साहर हिंदा होते होने साहर है। क्षा साहर है। सारपान समाव होन चाहरू हुआ होरा चाह चारचवन महा होना चाहरू। (१) कार निमावन । Refer to The Principle of Parliamentary Democracy, (1949),

- (2) जॉन लॉक एव उसके अनुयायियों का मत था कि स्वत तता व्यक्ति का ज मसिद्ध अधिकार है अत यह उचित नहीं है कि दूमरे व्यक्ति उस पर शासन करें। चिन सभी व्यक्ति समान हैं अत उन्हे शासन मे भाग लेने का अधिकार है। राज्य, लाक के अनुसार, सविदा का परिणाम है। सविदा की शत यह है कि सब लोग बहु संख्यकों की राम को माने । इस प्रकार लॉक ने सविदा के आधार पर लोकत त्र का समयन किया है।
- (3) उपयोगिताबादी विचारक के यम ने उपयोगिता के आधार पर लोकत न का समथन किया है। उसके अनुसार सभी लोग स्वभाव से स्वार्थी हैं और सूल पाहते हैं। राज्य का शासन थोड़े से लोगो अथवा एक व्यक्ति के हाथ मे होने पर वे उसका प्रयोग अपने वग या निजी हित के लिए स्वभावत करेंगे। विक सोकत प्र मे शासन मे समी का हिस्सा होता है अत सभी के हिता की पूर्ति हा सकेगी और सभी के स्वाथ भी पण हो सर्वेगे।
- (4) लीवतान का मनोवैज्ञानिक मुख्य है। शासन मे केवल दक्षता एव क्षमता ही काफी नही है। दक्ष एव योग्य शासको की स्थिति विशेषको जैसी होती है जी सिद्धा तवादी होते हैं। अच्छा शासन वह है जिसमे शासको व शासितो मे सहमोग हो तया शासको मे जनता के प्रति सहानुभूति हो । यह लोकतस्य मे ही सम्भव है। अपना शासन दूसर के श्रेष्ठ शासन से निश्चय ही अच्छा होता है। लोकत त्र मे जनता अनु-भव एव भूलो से िक्सा ग्रहण करती है, सामा यजन को शासन मे भाग लेने का अवसर मिलता है तथा उमकी इच्छाओ का सरलतापुनक पता चलता है। 64
- (5) लोकतात्र सावजनिक शिक्षा एव चरित्र के उत्थान का महत्वपूरण माध्यम है और सावजनिक शिक्षा की पाठशाला है। निर्वाचनों में विभिन्न दलों हारा सामाजिक एव राजनीतिक समस्याओ पर मायणो तथा पत्र पत्रिकाओं मे लेखी आर्दि हैं माध्यम से विचार प्रकट किये जाते हैं और उनके विभिन्न विकल्प प्रस्तावित किये जाते हैं। इससे सामा य व्यक्तियों को राजनतिक समस्याओं का ज्ञान होता है, सामान्य सुम-युक्त वढती है तथा उत्तरदायित्व की मावना का विकास होता है। सी डी इस नै अमुसार सभी शासनतात्र शिक्षा की पढितियों हैं परातु स्वशिक्षा सबग्रेष्ठ शिक्षा है बत थेप्ठ शासन लोकतात्र है जो स्वशासन है। SS
 - (6) जे एस मिल⁵⁰ के अनुसार अय किसी शासन की अपेक्षा लोकत प्र उच्च प्रकार ने राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है। ब्राइस का कथन था कि राजनीतिक गताधिकार से व्यक्तिया के सम्मान में वृद्धि होती है 167 डॉ आसीबीदम के अनुसार

⁵⁴ Gettell Political Science, 1956 p 201
55 Burns quoted by Dr. L. Asirvatham p 459
56 Mill J. S. Utilitarianism Liberty and Representative Government, (Fveryman's Edition 1948) Ch III, pp 211 215 57 Bryce Modern Democracues Vol 1, p 60

थेप्ठ शासन वह है जो व्यक्तियो नो नैतिन दृष्टि से शक्तिशाली, ईमानदार, परिथमी, आत्मनिभर तथा साहसी बनाता है। ऐसा बेवल लोबत य में ही सम्भव है। "

(7) लोकता वे अातगत देशमक्ति की भावना प्रवल होती है 1⁵⁹ साहित्य. क्ला एवं विज्ञान की उन्नति निरकशतानों की अपक्षा लोकतान में अधिक हुई है। मो टेस्क्य ने प्रेम को गणराज्य का एक अनिवाय लक्षण माना है। लीवतात्र में जान्ति एवं हिसात्मक परिवतन के लिए बहुत कम गजाइस होती है तथा सर्वधानिक रीति से वाछित परिवतन सम्भव होते हैं। विजनता को विचार एव भाषण तथा समाज और सम्मेलन आदि करने की पण स्वतायता होती है। गानर का कथन है कि लोकतायीय शासन अ य शासनी की अपेक्षा अधिक क्षमताबान शासन है क्योंकि लोकप्रिय निर्याचन. लोकप्रिय नियात्रण एव उत्तरदायित्व द्वारा ही अधिक सक्षम शासन सम्मव है। कोक साम में व्यक्ति के अधिकार एवं हित सुरक्षित रहते हैं। लोकतान निरक्रात नीय एवं अधिनायकतात्रीय ज्ञासनो की अपेक्षा अधिक स्थायी एवं प्रगतिशील है क्योंकि इससे निषय जनता करती है। यह व्यवस्था सर्वोत्तम है और जनता का निषय ही ईश्वर का निणय है।

लोकतत्र की आलोचना

लोकता नकी तीव्र आलोचना प्राचीन काल से ही की जाती रही है। निरक्ष-तात्र, अधिनायकतात्र एव कुलीनतात्र के समयको और साम्यवादियों ने लोकतात्र की

तीव निदा की है। मुख्य आलोचनाएँ निम्नवत हैं

(1) लोकता के आलोचकों में प्लेटो प्रमुख था। प्लेटों के अनुसार शासन के काय के लिए विशेष ज्ञान एवं चरित्र की आवश्यकता है। हर व्यक्ति उसके लिए योग्य नही होता । वह शासन का काम केवल विवेक सम्पन अभिजात्य वंग को सौपन का समयक या। उसका तक या कि हम जीवन की छीटी छीटी आवश्यकताओं के लिए विशेष ज्ञान एव अनुभव की आवश्यकता स्वीकार करते ह तो शासन जैसे महत्व-पुण काय को अनुमदहीन एव अविवेकी व्यक्तियों को वसे सौप सकते हैं ? लोकतान इसके विपरीत आदश को मानता है। प्लेटो लोकत त्र के आधारभव सिद्धा त समानता को नहीं मानता था। उसका मत था कि लोकतात्र में वास्तविक सख नहीं मिल सकता । वह तो उसी व्यवस्था मे प्राप्त हो सकता है जिसमे प्रत्येक व्यक्ति वह काय करता है जिसके लिए वह प्रकृति से सर्वाधिक योग्य होता है।

(2) लोकत त्र की 'अनत्तरदायी मीड का जासन' कहकर तीत्र आलाचना द की जाती है। अरस्तु इसे सर्वधानिक शासनी का विकृत रूप मानता है। मिल लोकत प्र

⁵⁸ Asirvatham of et, p 459 Laveleye Le Governnment dans la democratte, Vol I, p 273, quoted 59

by Garner of cit, p 358

'The virtue of the Republic is love"—Montesquieu The Spirit of the Laws, Book III and also Book V, Sabine of cit, p 469 60 Sidgwick Elements of Politics p 615 61

Garner Political Science and Government p 357 62

म बहुमत व अत्याचार से आत्वित था। लेकी (Lecky) र अनुसार लोकत प्रस्वत पता विरोधी शासन है। "लोक्त त्र मे गुणा की अपक्षा मता की अर्थात सस्या की अत्यिक महत्व दिया जाता है। मत गिने जाते हं, ताने नहीं जाते। विशेष प्रशिक्षण, विशिष्ट निणय एव विशिष्ट ज्ञान को कम महत्व दिया जाता है साकतात्र म शासन अज्ञानियो, अग्निक्षितो एव अयोग्य व्यक्तिया ने हायो मे होता है । लोकत य में सर्या का महत्व दिया जाता है। वह भीड का शासन है तथा मध्यम एव निम्न योग्यता को इसमे प्रथय दिया जाता है।"83 शोक्त य में बहमत सवर्धेष्ठ होता है और अपसा हुत अधिक विवेक एव थेप्ठ निणययुक्त अल्पमत की उपक्षा की जाती है। प्रिय निर्वाचन तथा अल्प कायकाल उत्तरदायित्व के लिए हितकर नहीं हैं। लोकत न सकीण दृष्टिकीण के व्यक्तियों का शासन है। सक्षेप में सावतात्र अज्ञानावस्या है।"

(3) लोकतत्त्र म ज्ञामनाधिकार पशेवर राजनीतिज्ञा एव नेताओं के हाथा म होता है अत व्यवहार मे लोकतात्र एक प्रकार का निकृष्ट अल्पतात्र है। तेलिस लोक त न नो नाले रक्षना ना नुलीनतान नहता या। एच जी बेल्स ने कथनानुसार लोक त न पाच मिनट म समाप्त हो सकता है। कार्लाइल लोकत प्र की मूर्ली का शासन मानता है। लोकत न में सीधे, ईमानदार एवं शान्त व्यक्ति चुनावों में नहीं चुने जाते अपितु वाचाल, बढ-बढनर गाल बजाने वाले, वान्पटु, जनता के रुख को देखकर मापण देने वाले एव मले को बुरा और बुरे को मला बता सक्ते में समय लोग सफल होते हैं। हटमान के अनुसार "शोर मचाने वालो, गण्यिया, बात मे से बात निकालने वालो, चापलुसी एव अमीरी के प्रशसको के लिए लोकत व स्वग है।"66

लोकतत्त्र मे श्रेष्ठ व्यक्तियो से घणा की जाती है। सामा य मतदाता को राज्य के कार्यों मे कोई रिच नही होती । फलस्वरूप चतुर एव चालाक लोग शासन हियमाने

में सफल होते हैं।

(4) सोकतान म दलीय व्यवस्था के कारण अनेक दोय उत्पन हो जाते हैं। देश में बगगत एवं दलगत स्वाय का बोलबाला होता है। चुनावों में छन कपट से नाम लिया जाता है। गदा एव दूपित प्रचार किया जाता है। राजनीतिक विरोधियी की हत्या तक कर दी जाती है। देसीय अनुशासन एव नियानण द्वारा जन प्रतिनिधि के व्यक्तिगत विवेक को समाप्त कर दिया जाता है। बाइस के अनुसार दलीय प्रणानी के फलस्वरूप लोकतात्र मे राष्ट्रीय दलगत विभेद एव अष्टाचार स्थानीय निर्वाचना तर्न

ner, flatterer and tust hunter "-Hartmann Tagesfragen, p 36

⁶³ Lecky Democracy and Liberty quoted by Garner op, cit, pp 363 64 and also see Forsyth, P T Socialism Church and Poor p 21 Assirvatham, E op est p 462
Talleyrand defined democracy as 'an aristocracy of black 64

guards and Carlyle referred to it as government of 'mostly fools HG Wells said it could be knocked to pieces in five minutes (Quoted by Garner op est p 356)
'Democracy is the paradise of the shrieker babbler, word spin 66

में फैल जाता है। नैतिक स्तर गिर जाता है और जनता में शासन के प्रति निष्ठा समाप्त हो जाती है। 67 बहदलीय पद्धति अस्थिर शासन का जाम देता है।

दलीय व्यवस्था के कारण मतदाताओं की निर्वाचन की स्वताताता भी सीमित हो जाती है, केवल दो-तीन उम्मीदवारा में से ही उसे अपने प्रतिनिध का चयन करना

पडता है। (5) कारोट (Faguet) लोकत न को 'अयोग्यो का शासन' कहता है। लोक-सात्र अयोग्यों का ही नहीं मुखों का भी शासन है क्योंकि बहसरयक व्यक्ति मुख हैं। यही नहीं लोकतान अनुत्तरदायी शासन है एवं इंड नीति निर्धारित करने में असफल रहता है। लोकत-त्र बेदेशिक मामलो, सरक्षा एव राजनय (diplomacy) की हप्टि से कमजोर शासन प्रमाणित हुआ है। यह नौसिखिया ना भी शासन है। ऐसे व्यक्ति शासन के पदो पर नियक्त हो जाते हैं जि हे शासन काय का कोई ज्ञान नहीं होता। 68

(6) लोकतात खर्जीली व्यवस्था है। इसमे धन व समय दोनो का ही अपव्यय

होता है।

(7) लोक्त न शिक्षा का नहीं अपितु कुशिक्षा का मान्यम है। लोगों में फठें अहकार की वृद्धि होती है। विनम्रता समाप्त हो जाती है, कुटिलता चारिनिक विशेषता बन जाती है। राजनैतिक जीवन मे अष्टाचार, वेईमानी एव क्चक का साम्राज्य होता है। सामा य शिष्टाचार भी समाप्त हो जाता है। लोगो में खशामद की प्रवृत्ति वढ जाती है। साहित्य, कला, विज्ञान, सम्यता एवं सस्कृति सभी का स्तर गिर जाता है। बास के अनुसार लोकतात्र जिस सम्यता को जाम देता है वह साधारण, सामा य एव निधित्रय है। ⁶⁹

(8) लोकतान व्यवहार मे धनी लोगो का शासन है। साम्यवादियों के अन-सार लोकतात्र में वास्तविक सत्ता धनिकों के हाथ में होती है। वे अनुचित तरीकों से धन खर्च करके मतदाताओं को प्रमावित करते हैं। लेकिन का मत या कि प्रजीवादी देशा का लोकतात्र सीमित, निधन एव भठा है। वशायिक समानता के अभाव म

राजनीतिक लोकतात्र केवल होग है।

(9) हेरेनशा के जनुसार अनितकता, अथदा, उद्दण्डता, असिंहण्पूता, स्वाथ एवं कृपणता लोकतात्र के कुछ अप दोष हैं। 71 साँड बाइस ने जो लोकतात्र के बड़े प्रशसक हैं, उसमे निम्न दोप बताये हैं

"The democracy in capitalistic society is curtailed, poor and 70 false ' -- Lenm

Bryce Modern Democracies refer to Garner op cit pp 367 369 67 88

Low Government of England pp 210 214
'The civilization which democracy produces is banal, mediocre 69 or dull '-Burns cited by Asirvatham op cit, p 466

[&]quot;Immorality irreverence, unmoderation intolerance selfishness, 71 and greed are other vices of democracy "-Hearnshaw pp 60-62

- (1) लोक्त न में घन से प्रशासन एवं विधानमण्डल का अप्ट कर दिया जाता है।
 - (2) राजनीति लोकतात्र मे एक लाभदायक पेशा है।

(3) प्रशासन अधिक खर्चीला होता है।

(4) समानता ने सिद्धात का दूरपयोग किया जाता है तथा प्रशासनिक कुश लता को महत्व नही दिया जाता।

(5) दलीय सगठनो की शक्ति अत्यधिक वढ जाती है जिसके फलस्वरूप भ्रप्टा

चार फैलता है।

(6) विधायक एव राजनीतिक अधिकारी विधि का निर्माण करते समय मता का पूण ध्याम रखते हैं एव विधि तथा व्यवस्था का उल्लघन करने वालो के प्रति भी सहिष्णता का बर्ताव किया जाता है। समीक्षा

नया प्रजात न की उपरोक्त आलोचना में सार है ? आशीर्वादम् का मत है कि कुछ आलोचनाएँ परस्पर विरोधी हैं, जसे कुछ लेखको के अनुसार लोकत त्र का अय बीर पूजा या उपासना है 3 तो दूसरो की हिन्ट में लोकत न दासता एवं अराजकता का पर्यायवाची है। कुछ वहते हैं कि लोकतान आदशवादी है एव उसमे अमूत आदशी की पूजा की जाती है⁷⁸ तो दूसरो का कहना है कि लोकत त्र में भावनाओं और सिद्धातो को नोई स्थान नहीं है। इन आलोचनाआ का परस्पर विरोध इननो खण्डित कर देता है। "लोकतान की समीक्षा करते समय निम्न तक ध्यान मे रखने चाहिए

(1) लोकत न से श्रेष्ठ अय नोई शासन पद्धति नहीं हैं। राजत त्र, हुलीन तान एव अधिनायकतान की अपेक्षा यह श्रेष्ठ पद्धति है क्योंकि इसमे व्यक्तित्व के विकास के लिए अनेकानेक अवसर हैं।

(2) निगत दो निश्व युद्धो, विश्वव्यापी गाँदी (1930) आदि जसे सकटो के

दोपा वे लिए केवल लोकतात्र की ही उत्तरदायी नही ठहराया जाना चाहिए।

(3) फागेट ने लोकत त्र की अयोग्यों का शासन वहा है। यह तच्यों के विप रीत है। लोकतात्र का अब यह नहीं है कि विशेषशों को शासन-काम से सम्बचित न विया जाये । सामा य जनता प्रशासन की वारीकियों को भने ही न समभती हो पर पु सामा य नीति एव सत्तारूढ शासन की नीतियो एव काय-पद्धति के बारे में उसकी निणय सही रहता है। लोकत त्र किसी विशेष जाति या वन के लोगा के लिए ही उपयुक्त शासन-पद्धति नही है।

(4) दलीय पद्धति सोकतात्र के लिए आवश्यक है। इसके फलस्वरूप अराज

⁷² Bryce Modern Democracies, (1929), Vol II, p 504 73 Hearnshaw op sit, p 59 74 Smith, A L The Empire and the Future, p 81 75 Asirvatham op sit p 468

बता व स्थार वर व्यवस्था उत्पन्न होती है। दलीय समस्याना वे प्रति राष्ट्र सजग रहता है एव दलीय अनुभाग सदस्या ने व्यक्तिगत स्वाय एव अप्टाचार पर नियात्रण लगा देला है।

(5) सत्य तो यह है कि लाक्त व व परीक्षण वा सही अवसर ही नही मिला है। उसने दोपा को बढ़ा नहां कर दिलाया गया है जबकि उसनी सफनताओं की उपका भी गई है। लागतात्र पर एक आराप यह है कि वह बुविक्षा के लिए उत्तरदायों है। यदि हम इस आरोप को मान लें ता भी हम यह स्वीनार करना पढ़ेगा कि अन्य शासन पद्मतियों म इससे भी वम शिक्षा वे अवसर हैं। लोग्तात्र म व्याप्त श्रय्टाचार वे लिए राष्ट्रीय चरित्र उत्तरदायी है न वि लोगतात्र । निकास

लोबत न अब तक मानवता को जात शासन की सबशेष्ठ पढ़ित है। परन्त यह सबधा निर्दोप नहीं है। लोक्त न वे दोषा यो दर यरा वे लिए और अधिक लोनत त्रीय व्यवस्था मी स्थापना एवं सस्थाओं ने विनास नी आवश्यनता है। समी देशा के अनभव हमें यह बताते हैं कि लोकत न से जो आयाएँ थी ने प्रण नहीं हुई है। कई देशों म लोगत य असमल रहा है और वहां सैनिय तानाशाही थी स्थापना हुई है। लोकत य की निरतर प्रशास करन वाले दशा-अमेरिका, इमलैण्ड आदि-मे स्वत प्रता. समानता, व्यक्ति की उच्च गरिमा के आदसी का केवल उदघीप किया जाता है वहाँ हे सामाजिक जीवन में नस्लगत घुणा एवं रंग भेद अत्यन्त गहरा है। यही मही यरोपीय लोकतात्रिक देशों ने एशिया व अफीका के देशों का निमय नापण किया है।

लोकत'न की संपानता के लिए एक विशेष वातावरण, चरित्र एवं कुछ अब-

स्याको की विशेष रूप से आवश्यवता है। वे निम्न हैं

"आर्थिक एवं सामाजिक समानता, शिक्षा, नारिको की देश की राजनीति म ली. आधारभूत एकता की भावना, स्वतन्त्र एव ईमानदार प्रेम तथा उच्चनीटि का र एवं व्यक्तिगत चरित्र।" मारत जस देगों में सोहत वही संपाना राजनैतिर की शहता पर निमर बरती है। डॉ॰ बाशीबान्य का मन है कि लोकनात्र की ता के लिए वास्ति नेताओं का चुनाब हाना चाहिए एवं बहुन अधिर मावजनिर इन भी नहीं होने चाहिए। " उपरोत्त मनी बानो का उस समय तर काइ मूल्य होगा जब तक कि समाज का नविक स्वर तक्वकोटि सा न हो समा ईमानदारी, गुता, उदारता एवं लोग-नत्याण की भावना जनमानम म व्याप्त न हा। जर अय विसी श्रेष्ठ शासन पढ़ित का विरास नहीं होना तम तर लारत म अपनी ों सहित ज्ञात शासन प्रणालिया में भन्येष्ठ शामन-पद्धति है। परन्तु नोस्टा मविष्य इस बान पर निमर करता है कि वह किस मीमा तक समाव म ता एव दू ल को दूर कर सकेगा।

Hearnshaw Democray at the Crossways J W Garner Science and Government 1951, pp 370 372 Asırvatham op cit, p 482

सविधान [CONSTITUTION]

हमम फाइनर वे अनुसार मौलिव राजनैतिव सस्याओ नी प्रणाली या प्रक्ति-सम्बन्धा की आत्मक्या ही सविधान है।"1

परिभाषा

विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न नाला म सविधान नी मिन्न मिन्न परिमापाएँ दी है। अरस्तु ने अनुसार सविधान विसी राज्य ने वाक्त अर्थात् सर्वोच्च प्रांकि नी बहं ध्यवस्या है जिसने द्वारा राज्य ने नाय सम्मादित किये जाते हैं। शासनों एव शासितों पर सिंधान ने माध्यम से नियं त्रण रदा जाता है। सासने ने निरष्ट्रणता मान्न माने अग से अनियत्रित शासन ना सविधान निरोध करता है। सवधानिक शासन ध्यवस्या का मौलिक एव आधारभूत सिद्धात यह है नि विधि सर्वोच्च है। चूरि विधि सम्मान रहित विवेच है अत उसना पासन सभी नो करना चाहिए। यदि शासन एक ध्यक्ति या कुछ व्यक्तिया नी स्विणन इच्छा पर आधारित है तो ऐसी स्थिन मे ध्यवस्या एव सुरक्षा का अमाव होना स्वामाविक है। अरस्तु ना यह नयन है कि 'इच्छा या आना (desire) जनली पशु है एव वासना अध्वतम सासन के मस्तियक नो भी पतित कर देतो है।'

आधुनिक विचारक गिलकाइस्ट के अनुसार "किसी राज्य का सविधान उन लिखित या अलिखित नियमो अचवा कानूनो का निकाय है जो सासन के सगठन एव उसके विभिन्न अमो के बीच शक्तियों के वितरण एवं उन सामाय सिद्धा तो का निर्धा रण करता है जिनके द्वारा इन शक्तियों का प्रयाग किया जाना चाहिए।"

¹ A constitution is 'the system of fundamental political institutions or 'the autobiography of a power relationship'—Herman Finer The Theory and Practice of Modern Government Methuen 1954 p 116

² The constitution is that body of rules or laws, written or unwrit ten, which determines the organisation of the government, the distribution of power to the various organs of government and the general principles on which these powers are to be exercised "Government and the general principles on which these powers are to be exercised."

डायसी वे श दो म ''सिवधान ने विधायी तत्व वे सार नियम हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य ने प्रभुत्व ने विभाजन अथवा प्रयाग नो प्रमावित नरते हैं।''³

पेटिल के अनुसार "विसी राज्य के उन आधारभूत सिद्धाता का नाम ही सविधान है जो उसके स्वरूप को निश्चित करते हैं। इन सिद्धाताका सम्यध राज्य के सगठन की पद्धित, सरकार के विधिन अगो के बीच राज्य की प्रभुशक्ति के विवरण, शासकीय कायक्षेत्र एवं उनके सम्पादन की पणाली तथा झासन एवं जनता के मध्य सम्बन्धों से होता है।"

क्रांतिक सविधान को उन कानूनो का सबह मानते है जिनके द्वारा राज्य के सर्वोच्च अगो का निर्धारण एव सगठन होता है तथा उसके पारस्थरिक सम्बधो, काम-क्षेत्रो एव राज्य के स-दम में उनके मौलिक स्थान का निरुच्य होता है।' ⁵

सोबियर (Bouvier) के अनुसार "सविधान दश की मौलिक विधि है। इसमे शासन के आधारभूत सिद्धातो, प्रभुसत्ता के प्रयोग के नियमो एव प्रभुसत्ता किन व्यक्तियो तक सीमित होगी आदि का उल्लेख किया जाता है।"

जॉर्ज कानवाल लेविस के अनुसार ''समाज मे प्रभुशक्ति की व्यवस्था एव वितरण अथवा शासन के स्वरूप का नाम ही सर्विधान है।''

^{3 &}quot;The constitution of a State consists of all rules which directly or indirectly affect the distribution or the exercise of sovereign power in the state '—Diccy, quoted by Majumdar B B Principles of Political Science and Government, 9th edn., p. 135

^{4 &}quot;The fundamental principles that determine the form of a state are called its Constitution. These include the method by which the state in organised the distribution of its sovereign powers among various organs of government, the scope and manner of exercise of governmental functions and the relations of the government to the people over whom its authority is exercised." —Gettell Political Science, (1956 edn.), p. 244.

⁵ The constitution is the body of the juridual rules which determines the supreme organs of the state, prescribes their mode of creation, their mutual relation, their sphere of action and finally the fundamental place of each of them in relation to the state in Jellinek, quoted by Garner of cit, p. 45.

⁶ A constitution m 'the fundamental law of the state directing the principles upon which the government is founded, and regulating the exercise of the sovereign powers directing to what bodies and persons these powers shall be confined and the manner of their exercise '—Bouvier Legal Dictionary', quoted by E Asirvatham of cit, p 349

^{7 &#}x27;The term constitution signifies the arrangement and distribution of sovereign power in the community or the form of the govern ment "—George Cornwall Lewis, quoted by Garner Political— Science and Government, 1951, p. 456

स्विस विद्वान चात्स बोर्गोड न अनुसार "सविधान मौतिन विधि है जिसने अनुसार राज्य ने झानन ना सगटन निया जाता है तथा समाज ने प्रति व्यक्तिया एवं नैतिन पुरुषा ने सम्बन्धा को निस्तित जिया जाता है। 'सविधान तिमित अभितेस के रूप मं भी ही सकता है जो सम्बन्धा निया खाता है। अवसा विधिया ने रूप मं मा हो सकता है जो सम्बन्धा निया एवं या अनेन विधिया ने रूप मं मा से अथवा 'यायिन निषयो एवं अध्यादेशा या परम्पराआपर आधित हो सकता है।

अमेरियन यायाधीय कूले वे अनुमार "राज्य वो मोशिय विधि मो सविधान कहत हैं जिसके सिद्धा ता द्वारा यह निरुचय विधा जाता है कि शामनतात्र किस प्रवार स्थापित किया जाये तथा विन व्यक्तियो वो किसने अधियार दिये जायें और वे उसका किस प्रकार प्रयोग करें।' 8

पायधीश मिलर ने अनुसार 'सविधान उस अभिलेख को शहते हैं जिसने आधारञ्जत सिद्धानों के अनुसार शासनत त्र नी मीनिन शक्तियाँ निश्चित, सीमित एव पारिमापित नी जाती हैं।''¹⁰

त्रिटिश यायशास्त्री आस्टिन ने सविधान की सक्षिप्त परिमापा करते हुए कहा है कि ''सविधान वह ध्यवस्था है जियके द्वारा सर्वोच्च शासन के सगठन की निहिचत किया जाता है।''

सर जेम्स मॉकटाश के अनुसार "सविधान उन समस्त तिखित व अलिखित आधारभूत कानूनो का सम्रह है जो उच्च खासनाधिकारियो के सर्वीधिक

^{8 &#}x27;A constitution is the fundamental law according to which the government of a state is organised and agreeably to which the relations of individuals or moral persons to the community are determined. It may be a written instrument, a precise text or series of texts enacted at a given time by a sovereign power or it may be the more or less definite result of a series of legislative acts, ordinances, judicial decisions, precedents and customs of diverse origin and of unequal value and importance "—Charles Borgeaud quoted by Dr. E. Asirvatham op. cit., p. 349, and Garner op. cit., p. 457.

⁹ Constitution is the fundamental law of state containing the principles upon which government is founded regulating the division of the sovereign power and directing to what persons each of these powers is to be confined and the manner in which it is to be executed —Justice Cooley quoted by Garner op at, p 456

^{10 &}quot;A constitution in the American sense of the word is ■ written instrument by which the fundamental powers of government are established limited and defined and by which these powers are distributed among several departments for their more safe and useful exercise for the benefit of the body politic "—Justice Miller, quoted by Garner op at, p 457

महत्त्वपूर्ण अधिकारो एवं जनता वे अधिवाय विनामाधिकारो का नियमन करता है।'¹¹

सरिवार गुरू का प्रयोग माना यत व्यापा एव सरीण अर्थो मे रिया जाता है। ब्यापर अर्थ म रिपी देश की सम्पूज शासर-व्यवस्था संगर्ध्यापन सभी निवमादि को जो शासन का स्वाप्ति, व्यवस्थित एव निवमित करते हैं, सविवार कहते हैं।

कोस्तितक व न इसी अब म निम्न सध्याम सिवधान री परिमाण प्रस्तुत की है—'सविषान से अब जा विधियो, सस्वाक्षा एव परम्पराक्षा र समूह से है जो मुनिश्चित विवर में मुद्ध सिद्धातो का परिणाम है तथा जिनके अनुमार विसी समाज ने अपनी सामन ष्यपस्या को स्वीकार किया है। "

व्यापन अर्थ में मुविधान सभी विधित (legal) एवं अविधिन (non legal) ियमो का सबह है। विधिक नियमा से अब ऐसे वियमा से है जो वायालय डारा माय होते है एय उनने द्वारा त्रियाचित नियं जाते हैं। अविधिन नियमा ने आतगत परम्पराएँ (customs) अभिगमय (conventions) साथि आते हैं। इन्ह संसदीय विधियों की अति यांगासया द्वारा त्रियाचित नहीं किया जाता । संगीण अय मे सविधार ऐसे विधिव एव लिखित नियमी का सबह है जा किसी देश के शासन का सचानत बरते हैं। प्राय सभी देशा में, ब्रिटेन का छोडवर, सविधान का सकीण अय प्रचलित एव माय है। ब्रिटेन में शामन के संचालन म आधारभूत विधिक एव अविधित सभी नियमों को सविधान था अग माना जाता है। परन्तु बतमान समय मे लिखित सविधानों की सुनिश्चित परिपाटी पड चुकी है। अत सविधान का सवमाय स्वीरत अथ उन विधिव नियमों के लेखबढ़ सबह से है जिनके अनुसार दशका शासन चलता है। ग्रेट ब्रिटन एव सबुक्त राज्य अमरिका के सविधान फमश व्यापक एव सकीण अथ वाले सविधाना में सबश्रेष्ठ उदाहरण हैं। सविधान की उपरोक्त गमी परिभाषात्रा म एक ही सार है। सविधान से बंब उन समस्त लिखित एवं अलिगित नियमो या बानना के समूह से है जिनके अनुसार देश का शासन चलता है। शागत के स्वरूप, उनके अमा के बीच गक्तियों का विमाजन, उनकी काय प्रणाती, मरकार एव नागरिको के बत्तव्य एव अधिकार समिधान द्वारा निर्धारित किय जाते हैं।

^{11 &}quot;The constitution m a body of those written or unwritten funda mental laws which regulate the most important rights of the higher magistrates and the most essential privileges of the subjects "—Sir James McIntosh, quoted by Carner of cit, p 455.

^{12 &#}x27;By constitution, we mean, whenever we speak with proposed and exactness that assemblage of laws, initiations and elected from certain fixed principles of rea on that connect the general system, according to which the community agreed to be governed '-Henry St. John, Vi. count Bodes quoted by H Finer op at. p 116

डा॰ आशीर्वादम ने अनुसार "सदिधान राज्य ने सामा य ढाँचे ना निर्धारण करता है अत उसे राज्य का ढाचा कह सकते हैं।""3

सी एफ स्टाग ने अनुसार "श्रेष्ठ सविधान मे निम्न तत्र आवस्यन हैं प्रथम, सरकार वे विभिन्न अग विस प्रकार संगठित विधे गये हैं। द्वितीय, इन अगी को क्तिनी शक्ति प्रदान की गयी है। तृतीय, हिम प्रकार शासन के विभिन्न अग शक्ति का प्रयोग करते हैं। मानव शरीर को स्वरूप (constitution) वहा जाता है एव जिम प्रकार विभिन्न अग शरीर वे स्वस्थ रहन पर ठीउ प्रवार से कार्य वरते हैं और शरीर के अस्वस्य होने पर ठीव प्रकार से बाय नहीं कर पाते हैं वही स्थिति गयियान की है। सविधान राज्य रूपी घारीर वा स्वरूप है जिसके अस एवं काम निश्चित होते हैं एवं जो निसी निरक्स शासक की इच्छा के आधीन नहीं होते।""

गानर का कथन है कि जिस प्ररार सविधान की भावना की चर्चा की जाती है उसी प्रकार कभी कभी सावजनिक नैतिकता एव चाय के उदात तथा उच्च सिद्धा तो मन्त्र भी आदश को सविधान की सजा दी जाती है। सविधान की मावना (spirit of the constitution) से तात्पय विसी अनुमानित ऐसे नियम एवं सिद्धा त से है जिसने अनुहुप सविधान ना सामाच स्वरूप होना चाहिए। जॉन स्टुअट मिल ने भी विचारों में इस कथन की भलव मिलती है। जिल ने सवैधानिक नैतिकता का उल्लेख किया है जिसका व्यावहारिक महत्व सविधान से किसी भी प्रकार कम नही होता।

सक्षेप मे, सविधान का उद्देश्य शासन के निरकुश कार्यों को भर्यादित करना, शासितों के अधिकारों की प्रतिभूति देना एवं प्रभुसत्ता के कायक्षेत्र की सीमा निर्धारित करना है।

सविधान की आवश्यकता

प्राचीन काल से ही यह स्वीकार किया गया है कि शासन के उन मौलिक सिद्धा तो को लेखबद्ध कर देना चाहिए जिनके अनुसार भावी शासन सचालित एव आधारित हो । आधुनिक यूरोपीय इतिहास मे 1579 ई का नीदरलैण्डस के संयुक्त प्राप्त का सथ अधिनियम इसका श्रेष्ठ उदाहरण है । स्मरणीय है कि अमेरिकी एवं फेंच क्रातियातक इस प्रकार के सौलिक सिद्धातों को सविधान की सज्ञा नहीं दी जाती थी। 1787 ई में सवप्रथम अमेरिकावासियों ने घोषणा की कि "हम संयुक्त राज्यों की जनता अमेरिकी समुक्त राज्य की स्थापना करते है।" उस समय से लिखित सविधान की परिपाटी पूरी तरह स्वीकृत हो चुकी है। सविधानो मे शासन के सगठन के सिद्धा'तो का उत्लेख होता है। यही सविधान का यथाथ अय है।

19वी मदी में त्रमञ्च यह धारणा बलवती होती गयी कि प्रत्येक राज्य की

^{&#}x27;A constitution fixes the general structure of the state it m so to speak, the skeleton of the state'—E Asirvatham Political Theory 1965 p 349

14 Strong C F Modern Political Constitutions 1963 p 12

बनता द्वारा अनुमोदित अपना सविधान होना चाहिए । ऐसा सविधान वतमान काल भवत हारा भवतात्वा भवता होना गाहर । रवा भवता व्यवस्था माना बाता है । सविधान की आवश्याता के निम्न कारण है— सविधान | 47

- (1) चासन की सक्तियां को सिवयान जैसे मौतिक कानून द्वारा ही सीमित करना सम्मव है। राजत नीय एव कुलीनत नीय युगो के अत्याचारी ने शासको की निरकुराता पर अकुस लगाना अनिवाय कर दिया था।
 - (2) व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा सिवधान हारा ही सम्मव होती है।
- (3) जॉन आदम, जेम्स मेडीसन एव सयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक याया धीशा ने इस बात पर बल दिया है कि बतमान एव माबी संवतियों की स्वेच्छा पर निय त्रण आवस्यक है। सविद्यान इस दावित्व को असी माति निमाता है। इसके विषरीत, जेक्रसन का मत था कि प्रत्येत्र सर्विधान का काल निरुष्टत होना क् जिससे वदस्ति हुई परिस्थितियों के अनुस्य जनता की उसे परिवर्तित करने सरलता हो।

सिविधान-हीन राज्य की आज कल्पना नहीं की जा सकती। प्रत्येक राजनीति समाज का अपना सविधान होना चाहिए।

गैदिल के अनुसार अच्छे सविधान के अनिवाय तस्व सुनिश्चितता (definite ness), त्रणता (comprehensiveness) विशिष्तता (brevity) तथा कोरता एव पुरिदत्तनशीलता ना सम्मित्रण (blending of flexibility and rigidity) है। द्वार्यसम्बद्धाः मः वान्यम् व व्यवस्थाः । वान्यम् व व्यवस्थाः । वान्यम् व व्यवस्थाः । वान्यम् व व्यवस्थाः । वा उपायमध्या म भव है के प्राचन के विविध होना बाहिए। विविध हमन फहनर विविध सविधान को अतिस्तित सविधान से अधिक महत्व नहीं देते। उसका कथन है कि जिस्ति विद्यान अपना च जानम् विद्यान (interpretations) के होरा परिवर्तित न विके अनुपति में ही एक सदम मापक का नाम कर सकता है। विकिन प्राम हर विमान में प्रति बस वर्षों में सतीधन एवं परिवधन होते रहते हैं। अतः बालिस्त

राता ने कार्य कर प्रयान संवाधना एवं पारवचन हात रहत है। वेद वा वा वाधावत . लिखित सविधान प्राय इस हैंदिद सं समान हैं। यही तक पूणता के सम्बर्ध में संस्य है। सिवधान निर्माताओं द्वारा अन्त काल तक प्रत्यक वात की व्यवस्था करना पन गरा है। । मर्ना, जहा वन करनव है। वाचवान, ज वन्त्रव जावनाव वर प्रवास्त्र एक सासन की सक्ति के प्रयोग से संस्वधित वातों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए और पुत्र भावा गा भावा व अभाग व क्षात्र भव भवा गा एकट व्यवन शाम भावपुत्र भार अनावस्यक विषया का विस्तात उल्लंख नहीं होना चाहिए। सविधान में केवल सासन व साठन के मीतिक सिद्धा तो का ही उल्लेख होना चाहिए, प्रशासनिक विषया का य प्रभाव र भावक विद्धा वा मा हा व्यवस्य होता आहर , नवावान विश्वस्य मा विस्तार से जल्लेस नहीं क्या जाना चाहिए। ज्याहरण ने सिए समुक्त राज्य क्योरिंग का सिवमान सिक्षात्वता का श्रेष्ठ उदाहरण है। उसम कवस मामनतत्र एवं जमने 15 Gettell R G op at pp 246-249 16 I'mer, H op al, p 127

तती

मे

7

सचालन सम्ब थी भौलिक सिद्धा तो ना हो उल्लेख है। इसके विपरीत, मयूवा ना सिव धान (1940 ई) एक लम्बा सिवधान है जिसमे 286 अनुच्छेद हैं। भारत के वत मान गणत त्रीय सिवधान (1951 ई) म उनसे भी अधिक 395 अनुच्छेट एव आठ परिक्षिक है। प्रशासकीय सिपया या सावजनित्न नियमो एव नार्यों से सम्बिधत वातो का उल्लेख सिवधान मे नहीं होना चाहिए। इनवी व्यवस्था ससदीय विधिया से की जानी चाहिए जिससे समाज वी परिवर्तित परिस्थितिया के अनुसार उनमें सरसता से परिवतन किया जा सके।

सविधान न तो इतना बठोर होना चाहिए कि परिवर्तित परिस्थितियों के अनु सार उसमें परिवर्तन या संशोधन न किया जा सके। साथ साथ वह इतना सुपरिवर्तन दील या लचीला भी नहीं होना चाहिए कि उसकी स्थिरता ही समाप्त हो जाय। अत सविधान में कठोरता एवं लचीलेपन का उचित मात्रा में सम्मिश्रण होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, 20वीं सदी में अच्छे सविधान म निम्न गुणो का होना भी

आवश्यक माना गया है

(1) सविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख होना चाहिए।

(2) स्वतंत्र एवं निष्पक्ष यायपालिका की व्यवस्था होनी बाहिए जिससे वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा हो सके।

(3) सविधान द्वारा अल्पसरयक वर्गों की सुरक्षा की पूच गारण्टी होनी चाहिए।

(4) सविधान में सामाजिक नीति का स्पटतापूर्वक उल्लेख किया जाना चाहिए। 20वी शताब्दी के मध्य से इसकी आवश्यकता को अनुमव किया जा रहा है। रूस, आयरलैण्ड एव फा स के सविधानों में सामाजिक नीति का उल्लेख किया गया है। मारत ने भी इन सविधाना से प्रेरणा प्राप्त करते हुए सविधान की प्रस्ता बना में मादी सत्तित्वा के लिए विधि निर्माण सम्ब भी आदश निर्धारित किये हैं। यह आदश है सामाजिक, आर्थिक एव राजनीतिक याग, अभिव्यक्ति के विद्यास, धम एव उपासना की स्वतान्ता, स्थित एव अवसर की समानता तथा भ्रातत्व जिससे व्यक्ति के व्यक्तिर एव राष्ट्र की एकता की रक्षा हो सके ।

(5) जापान के नवीन सर्विधान में जिसका निर्माण अमेरिकी प्रेरणा से हुआ है, युद्ध की हमेशा के लिए त्याग देने की घापणा की गयी है। विश्व शांति की दिशा में यह एक महत्वपूज कदम है। यदि प्रत्येत्र देश के संविधान में इस प्रकार का प्राविधान हो और उसका इंडतापूनक पालन किया जाये तो युद्ध की विमीपिका से बचा

जा सक्ता है। लेकिन इसकी जाशा प्राय नगण्य है।

में सी ह्वीयर (A. C Wheare) ने इस वात की विस्तार से चर्चा नी है। 17 उनने अनुमार एक आदश सविधान को अत्य त छोटा होना चाहिए । सत्य तो यह है कि सविधान का कोई एक स्वरूप सभी समुदायो के लिए न ता ब्यावहारिक ही हो सकता है और न उचित एव बाइनीय ही । पर तु बतामान एव भविष्य को घ्यान भ

¹⁷ Wheare K C Modern Constitutions 1966, Ch III, pp 32 51

रखते हुए प्रत्येव समुदाय ने लिए व्यावहारिक एव आदश सिवधान की क्ष्यरेका निश्चित भी जा मक्ती है। उदाहरण के लिए, एकात्मक शासन के सविधान। मे केवल शासन के साठन और उसके विमिन्न अभी के पारस्परिक सम्ब धो वी क्परेगा सामा पर शब्दों में व्यक्त भी जानी चाहिए। संघीय सविधान पर एकारम सिवधान को अपेशा वहा होना स्वाभाविक ही है। उसमे के द्वीय एव राज्या की सरकारों के केनाधिकार के स्ट्रस्ट उल्लेख के माथ आप व्यवस्थापिका की सीमा का भी उल्लेख होना चाहिए। प्रत्येक सव्यवस्थापिका की सीमा का भी उल्लेख होना चाहिए। प्रत्येक सविधान मे सशाधन की प्रणाली भी होनी चाहिए। स्मरणीय है कि सधीय देशा में सशाधन के प्रणाली भी होनी चाहिए। स्मरणीय है कि सधीय देशा में सशाधन के प्रणाली भी होनी चाहिए। इस व्यवस्थापिका को नहीं दिये जा सकते। एकारमक शासन की तुलता में सधीय देशों में न्यायपालिका की सिवित का स्पष्ट उल्लेख मी होना चाहिए। ह्वीयने के अनुसार सधीय सिविधानों में शासन सम्ब धी विधयों की केवल एक ही सूची होनी चाहिए तथा इस एक सुची के द्वारा ही केन्द्रीय सरकार या राज्या की मरकारों की 'तिस्की का उल्लेख किया जाना चाहिए। इस व्यवस्था का लाम यह है कि केन्द्र एव राज्यों में परस्पर विवाद के कम अवसर उत्पन होते हैं।

एकात्मक सविधान की अपनी कुछ समस्याएँ हैं जो सधारमक सविधान के निर्माताओं को भी कप्टप्रद हाती है। एकारमक सरकार की स्थापना करते समय जनता शासन की शक्ति को सीमित करना आवश्यक समभती है। फलस्वरूप सर्विधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारा का उल्लेख किया जाता ह और शासन से यह आशा की जाती है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू करे। शास्तु को उनमें हस्तक्षेप तो करना ही नहीं चाहिए। सविधान में भौतिक अधिकारी को लिपिबद्ध करने सम्बंधी अनेक समस्याएँ हैं। कौन मे अधिकार लिखे जायँ ?, उन पर नीन से और कितने अर्थात् किस सीमा तक प्रतिबाध होने चाहिए ? सोवियत रूस के सविधान ने अपने नागरिनो नो अनियात्रित अधिकार प्रदान निये हैं (अनुच्छेद 125) लेकिन वहा भी अधिकारो पर कुछ सीमाएँ , । इन सीमाओ से निरकुशता के लिए पर्याप्त गुजाइश रह जाती है। अधिकार यदि अस्पष्ट शब्दावली मे होते है तो उनका तिया वित करना कठिन होता है। ऐसी स्थिति उत्पार हो मकती है कि सविधान, यायालय एव व्यवस्था पिका में भाषा की अस्पष्टता के कारण विवाद उत्पन्न हो जाय। सविधान के बदनाम होने भी हर सम्भावना हो जाती है क्यांकि उसमे उटिलखित अधिकारा की पविजता नष्ट होने लगती है। अत ह्वीयरे के मतानुसार संयुक्त राज्य अमेरिका का अनुगमन **म**रते हुए स्वप्ट एव असदिग्ध शब्दावली में अधिकारी की गारण्टी दी जानी चाहिए। लेक्नि वहा भी सविधान मे 15वा सज्ञोधन अधिकारा सम्बाधी मापा की अस्पष्टता को दूर करने के लिए पारित किया गया था। हीयरे के अनुसार आदश सर्विधान मे थाडे से ही मौलिए अधिकारा ना उल्लेख होना चाहिए। उसने अनुसार यदि उनका भी उल्लेख न हो तो और भी अच्छा है। अधिकारा को सामाय विधि द्वारा प्रदान निया जाना चाहिए । इसने अतिरिक्त आदश सनिधान मे प्रस्तानना भी होनी

चाहिए। सयुक्त राज्य अमेरिका के सविधान निर्माताओं ने इस सम्बन्ध मे पहल की है तथा सयक्त राज्य अमेरिका के सविधान में अत्यात प्रमानकारी शब्दों में प्रस्तावना दी है। अनेक देशो जैसे पचम फ्रेंच गणराज्य स्विटजरलैण्ड, भारत आदि वे सविधानो में भी प्रस्तावना है। रूस का सविधान इमना अपवाद है। हीयरे का मत है कि "सवियान प्रधानत विधिक लेख्य है। सर्वोच्च विधि नियमो ना इसमे उल्लेख नही होना चाहिए । उसमे केवल विधिक नियमो का ही उल्लेख होना चाहिए। विधिक नियम मले ही थोडे अथवा सामाप्य हो सेविन मौलिक अवस्य होने चाहिए। सविधान की मापा सामा य होते हए भी निस्म देह मावकता से दूर होनी चाहिए !"18

सविधानो का वर्गीकरण

सविधानो के दो मुरय प्रकार हैं। प्रयम, लिखित एव अलिखित सर्विधान, 18 हितीय, सुपरिवतनीय (Flexible) एव दुष्परिवतनीय (Rigid) सर्विधान । ह्वीयरे[™] ने इन दो प्रकारों के अतिरिक्त निम्न प्रकार के सविधानों का और उल्लेख किया है

(1) सविधान जो व्यवस्थापिका से ऊपर हैं एव वे जो व्यवस्थापिका से ऊपर नहीं हैं।

(2) संघीय एव एकात्मक सविधान (Federal and Unitary Constitu tions) 1

(3) अध्यक्षात्मक एव ससदीय कायपालिका वाले सविधान (Presidential and Parliamentary Executive type Constitutions) t

(4) गणत तीय एव राजत तीय सविधान (Republican and Monar-

chial Constitutions) a

लिखित एव अलिखित सविधानो के अतर का आधार सविधान का लिखित या अलिखित होना है। सुपरिवतनीय एव दुष्परिवतनीय सविधानो का वर्गीकरण लॉड प्राइस की देन है तथा सविधान में संशोधन की रीति पर आधारित है। 🖹 सी हिमरे द्वारा दिये गये सविधानो के अप प्रकारो की यदि समीक्षा की जाम तो यह स्वीकार करना पडेगा कि सविधानों के उपर्युक्त विंगत दो प्रकार ही मुख्य हैं। ह्वीयरे हार उल्लिखित यह वर्गीकरण कि सविधान व्यवस्थापिका से उच्च है अथवा नहीं, सर्विधान के सपरिवतनीय एव दथ्यरिवतनीय वर्गीकरण के पर्याप्त निकट है। ह्रीयरे के वर्गीकरण का केवल यही अब है कि सविधान में व्यवस्थापिका द्वारा संशोधन किया जाना सम्मव है या नहीं । अत यह नोई नवीन एव महत्वपूर्ण वर्गीकरण नहीं है ।

सघीय एव एकात्मक सविधानो का वर्गीकरण के द्रीय सरकार एवं प्रातीय या क्षेत्रीय सरकारो ने मध्य बासन की शक्ति के विमाजन पर आधारित है। यह

18 Wheare, K C op cut p 51

20

स्ट्राय ने लिखिन एवं बनिश्चित सविश्वाना के लिए written और unwritten के स्पान पर documentary और non documentary माना का प्रयोग किया है।-Strong, C F op cit p 135 Wheare, K C op cit, Ch 2, pp 14 32

राज्यो का वर्गीकरण माना जाना चाहिए न कि सविधानो का क्योकि शासन प्रणाली ही राज्यों ने वर्गीनरण का स्त्रीकृत आघार होती है। अध्यक्षात्मक एव ससदीय काय-पालिका वाले सर्विधानो का आधार शक्ति प्रयक्करण (seperation of powers) है। स्मरणीय है कि सविधानों में शासन के केवल कायपालिका अग का ही उल्लेख नहीं होता । इसी प्रकार, गणतात्रीय एव राजतात्रीय वर्गीकरण मी शासन के दो प्रकारों की विशेषताओं का ही उल्लेख करते हैं। गणत नीय से तात्पय लोकत नीय व्यवस्था है तथा राजत त्रीय दासन निरक्शत न का प्रतीन है। यह शासन के प्रकार है न कि सविधान के।

काइनर के अनुसार सविधानों के स्वरूप से सम्बन्धित तीन मुख्य समस्याएँ है (1) सर्विधान लिखित है या अलिखित ? (2) सर्विधान सुपरिवतनीय है अथवा दुष्परिवतनीय ? (3) क्या सविधान की सर्वोच्चता सम्बाधी व्यवस्था उसम है ? इनमे भी मुख्य प्रश्न यह है कि सविधान वे विभिन्न स्वरूपों के अंतर का देश के राजनैतिक विचार एव व्यवहार पर क्या प्रमान पहता है ?21

लिखित सविधान निर्मित (enacted) होते हे जब कि अलिखित सविधान ऐतिहासिक विकास का परिणाम होते है। इन्ह 'cumulative' की सज्ञा दी जाती है। अलिखित सर्विधान का एकमान उदाहरण ग्रेट ब्रिटेन का सर्विधान है। सबक्त राज्य अमेरिका, मारत, रूस आदि के सविधान लिखित सविधान के उदाहरण हैं। अलिखित सविधान का अधिकाश अश लिखित रूप म नही होता है और न उसका निर्माण किसी निश्चित समय में योजनावद्ध रीति से किसी सविधान सभा या इस हेतु आहत सम्मेलन द्वारा ही होता है । अलिखित सविधान प्राय प्राचीन परम्पराओ, रीति रिवाजो, रूडियो, यायिक निणयो एव समय समय पर निर्मित ससदीय विविधा का पुज होता है। वह राज्य ने ऐतिहासिक विकासकम ने साथ विकसित होता रहता है। ग्रेट ब्रिटेन के सविधान का इसी प्रकार विकास हुआ है। अलिखित सविधान कोई विधिवत् लिपिवद्ध लेरय नही है। अत अलिखित सविधान के ज्ञान के लिए राज्य के ऐतिहासिक विकास से परिचित होना आवश्यक होता है । गानर ने अनुसार "अलिखित सविधान की सभी नही बरन अधिकाश बातें कभी किसी लेख्य या लेखों के सग्रह के रूप मे लिपिबद्ध नहीं नी जाती।" अलिखित सविधान सर जान मिकटाश के इस कथन को सबया चरिताय करता है कि "मविधान जाम लेते हैं, बनाये नहीं जाते।"ध

लिखित सविधान एव उनका विकास

फाइनर के अनुसार लिखित सविधानों ने विकास के दो प्रमुख कारण होते हैं-प्रथम, समाज के प्राचीन बक्ति सम्बाधो (power relationship) के पतन के परचात

²¹

Finer, H op cit p 118 Garner Political Seionce and Government, Indian edn , 1951, p 464 McIntosh, Sir John , quoted by Garner op cit , p 464

52 | आयुनिक शासनतात्र

नवीन शक्ति सम्बन्धों का उत्य होता है। इन सम्बन्धों को सुनिश्चित एव स्पट करने के लिए उ हे लिपिबढ़ कर दिया जाता है। द्वितीय, अनेक राज्यों द्वारा एक इकाई के रूप में सगिटित होकर अप्राप्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एव राजनीतिक व प्रशासिन अप व्यय को रोकते तथा आपसी मतभेदों का दूर करने के लिए सभी से सम्बन्धित कार्यों एव तत्सम्बन्धी परिस्थितियों को सिवधान में लिपिबढ़ कर देना श्रेयस्कर समभा जाता है। सपुत्त राज्य अमेरिका एव स्विट्जरलैंड के परिसद्य तथा आस्ट्रेसिया ने कॉमनवैत्य के सविधान इसने उदाहरण हैं। 14

1919 ई के जमनी के बीमर सविधान (Weimar Constitution) के उदय के भी उपरोक्त कारण थे। स्मरणीय है कि जमनी म प्रचलित एकत तीय व्यवस्था के स्थान पर उससे श्रेष्ठ परात नवीन सघीय व्यवस्था का निर्माण किया गया था। भारत के नवीन समिधान (1950 ई) के उदय में भी उपरोक्त दोनों कारण काय कर रहे थे। प्रथम, स्वतात्रता प्राप्ति के साथ नवीन सामाजिक सम्बाधा का उदय हुआ था। यह सम्बाध ब्रिटिशकालीन शनित सम्बाधा से सवया मिन्न थे। द्वितीय, निर्देश भारत के प्राप्त एकात्मक शासन व्यवस्था के आधीन ये जबकि देशी रियासतें 15 अगस्त 1947 के बाद पूण स्वत[ा]न हो गई थी । इस स्थिति को समाप्त करने के लिए मारतीय सवि-धान निर्माताओं ने सघीय व्यवस्था की स्थापना की थी । यह नवीन शक्ति सम्बन्ध पराने सम्ब घो नी अपेक्षा निश्चय ही श्रेष्ठ थे। 1936 ई का सोवियत रूप का 'स्टालिन सविधान' समाज के नवीन शक्ति सम्ब धो की स्थापना का स्वामादिक परिणाम था। 1925 ई तथा 1936 ई के इसी सविधान में स्पष्ट अंतर है। 1925 ई के इसी सविधान की भाषा न समय की स्पष्ट भलक दिखायी देती है जबकि 1936 ई के सविधान में यथास्थिति को स्वीकारने की ध्वनि निक्सती है। 1936 ई के रूसी सिवधान ने निर्माण के समय तक रूसी कार्ति एक वास्तविक ऐतिहासिक तथ्य बन चकी थी।25

लिखित सविधान का प्रयम प्रमत्न 1649 ई में इसलैण्ड में किया गया या स्वयंपि इस सविधान (The Agreement of the People) का निर्माण अक्टूबर 1647 ई में हुआ था। ससदीय सेना क अिकारियों की मिनित (The Council of the Parliamentary Army) हारा 1649 ई में इस सविधान का स्थोहत किया गया था कितन यह त्रियाचित नहीं हो सबा । 1653 ई में शासन का तरें (The Instrument of Government) नामन एक अय सविधान त्यार किया गया था। यह लितित सविधान का इसरा उदाहरण है। यह भी अल्युक्तानीन सिंद हुआ और 1660 प्रिंग में स्थानिक में राजतान की युनस्थामना के साथ इसका अत्त हो युवा। इसलेण्ड में राजतान की युनस्थामना के साथ इसका अत्त हो युवा। इसलेण्ड में

²⁴ Finer, H op est p 119
25 निया अनुन्देन भे । इस अनुन्देन ने आयोग सावियत सम स पूँजीवान वा अन वर निया गया है और निया स्वासिय के क्यान पर सामृत्वि क्यायित की स्थापना की गई है तथा व्यक्ति का अर्थात हारा घोषण समान्द कर निया यथा है।

आज अलिबित सर्विधान का एकमान उदाहरण है, वास्तव मे, 'लिखित सर्विधानो की जननी भी है।" 6

आधुनिक लिखित सविधाना के प्रथम उदाहरण अमेरिकी उपनिवेशों के विभिन्न सर्विधान हैं। इनका निर्माण ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने के पश्चात किया गया या। 1776 ई मे फिलाडेल फिया ना फ्रेस ने यू इगलैण्ड के प्रतिनिधि श्री जॉन आदम (John Adams) के प्रस्ताव को स्वीकार किया था जिसके द्वारा उपस्थित प्रतिनिधियों को अमेरिका एव विभिन्न घटक इकाइयों की जनता की सुरक्षा एवं सुख को घ्यान म रखते हुए शासन के निर्माण का आह्वान किया गया या। जून 1776 ई में अमेरिका के वर्जीनिया (Virginia) नामक राज्य ने पू हैम्पशायर (New Hampshire) एव दक्षिणी कैरोलिना (South Carolina) का अनुगमन करते हुए सविधान का निर्माण किया था। इस सविजान की अपनी विशेषता यह थी कि इसमें अधिकारी की घोपणा (The Declaration of Rights) की गयी थी जो परवर्ती अमेरिका एव यूरोपीय सविधाना के लिए उदाहरण वन गयी।

फ्रांस को अमेरिकी स्वातान्य घोषणा एव विभिन्न राज्यों के सविधानों से प्रेरणा मिली थी। जलिनिक ^र के अनुसार अधिकारो की घोषणा की प्रेरणा फास की अमेरिकी घटनाओं से प्राप्त हुई थी। 1789 ई मे फ्रांस में सामातवादी व्यवस्था ने विरुद्ध शान्ति हुई जिसने फलस्वरूप नवीन सामाजिक सम्ब धो का उदय एव नवीन सर्विशान का निर्माण हुआ। फ्रासीसी चारितकारिया की मापा में अमेरिकी कार्ति-कारियों ने शब्द प्रतिव्वनित होते थे । 2 अन्टबर, 1789 ई को फेच सविधान समा ने नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की। इस सविधान की प्रस्तावना में लिखित सविधाना के सभी अनिवाय लक्षणा का उल्लेख था। फ्रान्स मे 1789 ई मे पूणत लिखित सविधान लागू हजा था। 1875 ई मे तृतीय गणराज्य का उदय हुआ था और यह फास का 13वा लिखित सविधान था।

लिखित सर्विधान एक पवित्र सेख होता है जिसमे अधिकाश आधारभत सिद्धा त भीपचारिक रूप से तिपिवद कर दिये जाते ह । लिखित सविधान मे नामन के विभिन्न अगो-ध्यवस्थापिका, कायपालिका, यायपालिका-ने सगठन, शक्तियो एव कत्रव्यो व नायप्रणाली, नागरिना के अधिकार आदि को भली प्रकार लिपिबद्ध कर दिया जाता है। जेम्सन के अनुसार ' लिखित सविधान एक ऐमा निश्चित प्रयास है जिसने द्वारा शासन को सगठित एवं सचालित करने वाले आधारभूत सिद्धा तो का सूजन किया जाता है।"29

²⁶ Finer, H op at, p 120

²⁷

Jellinek, George, quoted by Finer op at, p 121 पाइनर ने अनुसार फास द्वारा सवशयम यूरोप म विखित सविधाना का उदाहरण प्रस्तुत क्या 28 गया या ।-op at, p 122 29

A written constitution "is a work of conscious art and the result of a deliberate effort to lay down a body of fundamental principles under which government shall be organised and conducted -Jameson quoted by Garner op at, p 464

लिखित सविधान वाले देशों में सामा यत सवैधानिक एवं ससदीय दोनों प्रकार की विधिया पायी जाती हैं।

क्या सविधानो का लिखित एव अलिखित का भेद उचित है ?

लिखित एव अलिखित सविधानों का बतर सी एफ स्ट्रांग के अनुसार भ्रामक तथा मिन्या है नयीकि कोई भी मिनधान न तो पूणतया लिखित होता है और न अलिखित हीं। निधित सविधान सामा यत उसे कहते हैं को एक लेख्य के रूप में उपलब्ध होता है और जिसे अपेसाइत व्यक्ति महत्ता प्राप्त होती है। अलिखित सिंध धान का लिखित सविधान की अपेखा परम्पाता हारा विकास होता है। निखित सविधानों को सविधान-निर्माताओं द्वारा प्रत्येक स्थिति के अनुरूप अधिनाधिक पूण यनाने का प्रयत्न किया जाता है। बुख विखित सविधान एसे भी होते हैं जो सविधान-निमाताओं द्वारा निमित अथवा स्थीहत अनेक भौतिक विधियों में निहित होते हैं।

डगलैण्ड के अलिखित सविधान मे अनेक अश्र लिखित हैं, जैसे—मैगना कार्टी (1215 ई), 1689 ई वा अधिकार पत्र (Bill of Rights), 1701 ई का उत्तरा- धिकार अधिनियम, 19वी सदी के विभिन्न मताधिकार अधिनियम, 1911 एव 1949 ई के ससरीय अधिनियम इत्यादि । इनके कारण इगलण्ड के सियान में भाफी अत्तर पड़ा है। इसके विचरीत, समुक्त राज्य अमेरिका का सिवधान पूणक्षेण लिखित होते हुए भी अलिखित अभिसमयो एव परम्पाशा हारा विकसित हुआ है। उवाहरण के लिए भी अलिखित अभिसमयो एव परम्पाशा हारा विकसित हुआ है। उवाहरण के लिए सिवधान ने अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मण्डल ने सदस्यो के बहुमत हारा होना चाहिए जो कि जनता हारा चुने जाते हैं। व्यवहार मे स्थित इससे भिन्न है। प्रत्येक राजनीतिक दल राष्ट्रपति वर के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करता है और दल हारा उसी ने पक्ष मे प्रयाप मि निया जाता है। जनता हारा निर्वाचक-मण्डल के सदस्यो को क्लीय आधार पर चुना जाता है और सदस्य अपने दल के प्रत्याशी को स्थायों को स्थायों के सहस्यों को दलीय आधार पर चुना जाता है और सदस्य अपने दल के प्रत्याशी को ही मत देते हैं। फलस्वरूप राष्ट्रपति का निर्वाचन व्यवहार में परम्पार के कारण जितका सविधान मे नहीं उल्लेख नहीं है, प्रत्यक्ष रिति से होने लगा है।

हमन फाइनर इस मत से सहमत प्रतीत नहीं होते । उनके अनुसार इपलैण्ड का सिवपान स्वीहत तेवल के रूप में भाग नहीं है । इमलण्ड को राजनीतिक सत्याएँ गामिन निणया एव सत्योग विधियो हारा ध्यवस्थित की जाती हैं । इसके अतिरक्त अतेक प्रवास के अनेक महत्वपूण भागा को ध्यवस्थित विधायो होता सिवधान के अनेक महत्वपूण भागा को ध्यवस्थित विधाय जाता है । ससद की सप्रभुता एव मिन्मण्डकोय उत्तरदायित्व के सिद्धात मी अभिसमया पर ही आधारित हैं । स्मरणीय है कि अभिसमया के विपरीत गामिल निणम एव ससदीय विधियो लिगित होते हैं । ब्रिटिश सविधान अनेक लिखित सिविधानो से नहीं अधिक स्थव प्रयास है। अभिसमय अभिसित्त होते हुए भी मुस्पट हैं। इन अभिसमया को स्वर्धा अथवा भागणो म विधानी है । इसके अभिरक्त अववा भागणो म विधानी है । इसके अतिरिक्त, अनेक सविधान सांस्था एवं विद्वानी—जोते.

³⁰ Strong, C T op at, pp 66-67

हैं तो अमेरिका के लिखित सविधान में अनेक परम्पराओं का विकास हजा है एवं हा रहा है।

(2) लिखित एव अलिखित भेद को माने का जय है कि लिखित रूप में सविधान न होने पर सविधान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यही खो टास्विले (de Tocqueville) का 1834 ई मे मत था। इसके विपरीत, इंगलण्ड का सविधान अग्रत लिखित एवं जज्ञत अलिखित है।

(3) इस अत्तर का एक अन्य निष्कप यह है कि विधि का लिखित रूप में होना अनिवाय है एव विधि का अलिखित होना उचित नहीं है। स्मरणीय है कि विधि परम्परा पर भी आधारित हो सकती है, विधान (legislation) ही विधि ना एकमात्र स्रोत नहीं है।

स्परिचतनीय एव दृष्परिचर्तनीय सविधान

सशोधन प्रणाली के आधार पर सविधानो को सुपरिवतनीय एव दुष्परिवतनीय में भी वर्गीकृत किया जाता है। लॉड बाइस³⁴ ने संवप्रथम सर्विधानों को संशोधन प्रणाली के आधार पर वर्गीकृत किया था। जिन सविधाना म सामान्य विधि प्रक्रिया के दारा सशोधन सम्मद होता है उन्ह लचीला या सुपरिवतनीय सविधान की सक्षा दी जाती है। इसके विपरीत, जिन सविधानों में संशोधन की विशिष्ट प्रणाली होती 🖡 जो सामा य विधि प्रक्रिया सं मिन हाती है उन्हें कठोर या दुष्परिवतनीय सर्विधान कहा जाता है।

सुपरिवतनीय या लजीने सविधानो म सवैधानिक विधि (Constitutional law) एवं ससदीय विधि (Statutory law) में विधानमण्डल द्वारा साधारण तरीने से परियतन किया जा सकता है। लेकिन कठोर सविधानो म सशीवन की विधि साधारण विधि प्रणाली की अपेक्षा जटिल तथा पृथक होती है । दुष्परिवतनीय सविधान सामाय काननों की अपक्षा अधिक पवित्र माने जाते हैं। उदाहरण के लिए, इंगलण्ड म विधि निर्माण के लिए एक ही विधि प्रकिया का अनुगमन किया जाता है, मले ही यह विधि किसी सामा य प्रशासनिक समस्या से सम्बन्धित हो या हाउस जाफ लॉड स की शक्तिया म परिवतन से सम्बन्धित हो। स्ट्राग के अनुसार "इगलैण्ड म प्रथक सबधानिक विधि जसी कोई बीज नहीं है । अत इगलण्ड का सविधार सुपरिवतनीय है । अ लचीले सविधान का दूसरा उदाहरण यूजीलण्ड का है। यूजीलण्ड का सविधान निखित है लेकिन सदाघन प्रणाली सरल है । इसी प्रकार, इटनी का पुराना सविधान भी लचीला है। राजत त्रीय इटली का सविधान लिखित था लविन उसम संशोधन या परिवतन की कोई पृथक प्रणाली नहीं थी। यह सविधान इतना अविक लचीला था कि मुसोलिनी सविधान की मावना नी उपक्षा किय विना ही उसका उल्लंघन करता रहा। अत यह निष्क्षप निकलता है कि सर्विधान लिखित होने पर भी लचीला हो सकता है।

35 Strong Modern Political Constitutions (1963) p 68

Flexible and Rigid Constitutions, p 11, quoted by Garner 34 Bryce op cit, p 470

इसके विपरीत, सविधान के बहुत कम लिखित होने पर भी उसम सकोशन करना जिटल हो सकता है जसा कि तृतीय का सीसी गणराज्य का सविधान । यह बहुत कम लिखित होते हुए भी कठोर था क्यांकि सर्वधानिक सबोधन के लिए इसम विशेष प्रणाली का उल्लेख किया गया था। यह आवश्यक नहीं है कि लिखित सविधान दुष्परिवतनीय ही हो। लिखित सविधान दोना ही प्रकार के हा सकते हैं।

दुप्यरिवतनीय सिविशानों के कुछ अ य उदाहरण निम्नवत ह सयुक्त राज्य अमेरिका, चतुन एव पचम का सीसी भणराज्य, स्विट्यर्सिण्ड, आस्ट्रेलिया, रूस एव नेपाल के सिव्यान । रूस के सिव्यान में सखीधन सुप्रीम सीवियत के दीना सदनों के दी तिहाई वहुमत से किया जा सकता है। सयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्यर्स्तण्ड एव यास्ट्रेलिया के सिव्यान में सखीयन की विशेष प्रणाली है जो साधारण विधि प्रक्रिया की अपेक्षा जटिल है। उपरोक्त तीना देखा में सधीय विवानमण्डल द्वारा ही केंवल सवैधानित सत्तीभन नहीं किय जा सकते अपितु इसके लिए अप्य निकायों एव व्यक्तियां का सहयोग अपेक्षित होता है। चतुष का सीसी मणराज्य का सविधान (1946 ई) भी हतीय गणराज्य की माति ही कठोर था। पचम का सीसी गणराज्य का सविधान मी कठोर है यदापि इसमें सवधानिक सत्तीधन सम्बन्धी कुछ शक्ति राष्ट्रपति को भी कठोर है यदापि इसमें सवधानिक सत्तीधन सम्बन्धी कुछ शक्ति राष्ट्रपति को भी प्रदान की गई है।

यह वर्गीकरण अपक्षाकृत अधिक तक्समत एव वैद्यानिक है। सी एफ स्ट्राग इस सिवधान का सही वर्गीकरण मानता है। ¹⁸ ह्यूपिर ने भी इस वर्गीकरण को उचित एव वाक्ष्मीय भेद पर आधारित माना है। सुपरिवतनीय एव दुष्परिवतनीय सिवधानो का भेद मात्रा का न होकर प्रकार का है।²⁷

लिखित सिवधान सामा यत कठोर एव दुष्परिवतनीय हाते है। यूजीलैण्ड का सिवधान इसका एकमान अपवाद है। श्रेप सभी लिखित सिवधान कठोर हु। इसी प्रकार, अणिखित सिवधान सुपरिवतनीय होते है। अत लिखित एव दुष्परिवतनीय तथा अिलिखित एव सुपरिवतनीय तथा अिलिखित एव सुपरिवतनीय सिवधानों के गुण दोष समान है। लिखित एव अलिखित सिवधानों के गुण दोष की सीक्षा कर के हम सुपरिवतनीय एव दुष्परिवतनीय सिवधानों के गुण दोष की सी समीक्षा कर सकते है।

असिखित एव सुपरिवतनीय सविधान के गुण-—(1) समाज की वदसती हुइ सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार इन सविधाना में परिवतन सरसतापूर्वक एव बीघ्रतापूर्वक सम्मव होता है। फलस्वरूप कार्ति की सम्मावना नहीं रहती।

(2) ब्राइस कं अनुसार "जिल्लाित सिवान को सत्रमण-नाल म बिना उसका डांचा तोडे परिवितित था सत्रोधित किया जा सनता है। सकट-काल के बीत जान पर व पुन अपने पूत्र जाकार को ठीक उसी प्रकार प्राप्त कर लेत हुं जैसे हिसी गाडी को

³⁶ Strong op at p 67 37 Wheare op at p 16

गुजरने के लिए किसी पड़ नी टहनी को एक सरफ हटान के बाद माडी के गुजर जाने पर टहनी पून अपना स्थान स सेती है।™

(3) सुपरिवतनीय होन के बारण सिवधान की उपशा करने का भाव साधारणत जनता में जागृत नहीं होता ।

(4) गिलकाइस्ट ने अनुमार 'वे राष्ट्रीय मस्तिष्ट को नती प्रवार प्रति-विभिन्न करते हैं। य सविधान अतीत पर आधारित होते हैं, वतमान म सिन्न रहते हुए एव मविष्य पर इष्टि रखते हुए शासन सम्बची बतमान धारणाना तथा सामा-जिक एव राजनीतिक स्वत त्रता सम्बची मिद्वा तो को अनिव्यक्त करते हैं। "

बोय-(1) यह निरत्तर परिवर्तित होत रहत है अत अस्यायी एव अनिश्चित

होते है।

(2) राजनीतिज्ञा एव दला वी इच्छा पर इनम सरलतापूवक परिवतन होते रहत हैं। सिअविक के दा दो म इन सविधानो म "जन विरोध के शणिक भोको से महत्वपूण सिद्धा तो एव सस्याओं का उभावन हो सकता है तथा प्राचीनता एव परम्परा द्वारा प्रदत्त स्थिरता का सहज ही अत हो जाता है।"

(3) अलिखित सर्विधान लोकत नीय समाज की अपेक्षा कुलीनत नीय समाज

के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं।

(4) अलिखित सिवधान परम्पराबो एव किंदियो पर आधारित होता है। इसलण्ड के अलिखित सिवधान का विगत 200 वर्षों य काफी माग लिखा गया है। देम्परले के शब्दों में "किसी देश का अलिखित सिवधान दो कारणों से अल्यिषक स्वतरताक होता है। प्रथम, रुदिया के दो अय सम्मव होते हैं जबकि कानून के केवल एक ही अय होता है। सिद्धा तहीन एव दुस्साहभी राजनीतियों को सवैधानिक रुदिया के दे इस्ताहसार सामा होते हैं। इस्ताह की सम्मव होते हैं प्रतिश्व की सिवधानिक की स्वाधारण कानून एव सवैधानिक की स्वाधारण कानून एव सवैधानिक की मानूनों में सशोधन करने की एक ही प्रतिया है।

(5) अलिखित सिवधानो में जनता को अधिकारा का आदवासन नहीं दिया जाता है तथा सावजनिक कमजारियों को निषय करने की अधिक स्वट नता प्राप्त होती है। ब्राइस के अनुवार ये सविधान यावाधीया के हाथ का खिलीना होते हैं।

लिखित एव दुष्परिवतनीय सविधानो के गुण-(1) यह स्पष्ट एव सुनि-

श्चित होते हैं तथा उदास राजनीति का परिणाम होते हैं।

bent so as to meet and when the form like a let a 479

³⁸ Flexible constitutions emergencies without 1 emergency has passed tree whose control p

³⁹ Gilchri

⁴⁰ Sidgwi

⁴¹ Bryce,

- (2) इनम सावजनिक भावावेश या ससदीय निरकुशता के फलस्वरूप शीष्ठता-प्रवक्त उप्र परिवतन या सशोधन नहीं किये जा सक्ते 1⁴
 - (3) यह अधिक स्थायी व स्थिर होते है।
- (4) लिखित सर्विधान का निर्माण किसी समा या समिति द्वारा बहुत सोच-समफ्र कर एव वाद विवाद के पश्चात किया जाता है अत उनके अथ के सम्बन्ध में अधिक मत्रभेद की गजाड़भ नहीं होती।
- (5) सिखित सविधाना में सामा यतया नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख होता है। अत इन सविधानों द्वारा नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की कहीं अधिक गारण्टी दी जाती है जिससे आसन निरक्त एवं अत्याचारी नहीं हो सकता।
- (6) समीय राज्या के लिए लिखित सिवधान ही अधिक उपपुक्त है। समीय सिवधान में शासन के विकित अगो के अधिकारों में सरलतापूरक परिवतन सम्मय नहीं। होते हैं और न एक दूसरे के अधिकार क्षेत्रा का उल्लावन ही सरल होता है। ⁶⁸
- (7) लिखित सिवधान मे सभी व्यवस्थाएँ लिपिबड होती है। अन किसी विषय के सन्दम मे विवाद की स्थिति म सर्वोच्च यायपालिका का निणय अतिम होता है।
- बोप—(1) लिखित सिव्यानों का सबसे बड़ा दोप यह है कि वे प्राय जिटल होते हैं। समय की गित के साथ जनम परिवतन नहीं हो पाते। यह दोप एकात्मक राज्यों की अपेक्षा स्थापनक राज्यों में अधिक पाया जाता है क्योंकि केन्द्र एव राज्यों के सम्य चिक्त निकाल के कारण अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। मकाल के अनुसार "नातियों का एक बड़ा कारण यह है कि जब राष्ट्र आगे बढ़ते जाते हैं तो सिव्यान दिया की पहुं है ।" अ गानर के अनुसार "विधित सविधान ऐसी पोशांक की माति हैं जो ब्यक्ति के आकार, विकास एव परिवतन को ध्यान में रखे बिना बनायी गयी हो। "
 - (2) लिखित सविधान की व्याप्या सरल नाय नहीं है। यह दायित्व सामा-यत पायपालिका का सामा गया है। यावाधीशो का हिन्दकीण साधारणतया रूढिवादी होता है। फलस्वरूप पायपालिका एक तृतीय सदन बन जाता है।" लासकी का मत है कि यायाधीश परिवर्तित युग की भावना का प्रतिनिधित करने मे असफल रहे हैं। वे अपेसाकृत सविधानों के निर्माण के युग की ही मावना को अभिव्यक्त करते हैं और यदि परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप उनके द्वारा सविधान की ब्याप्या

⁴² Garner op cut p 478

⁴³ Lasks Grammar of Politics (1941), p 306

^{44 &}quot;The great cause of revolutions is this that while nations move onwards constitutions stand still "-Lord Macaulay, quoted by Carner op at (1951), p 478

⁴⁵ Written constitution "is like an attempt to fit a garment to an individual without taking into consideration its growth and size"—Garner op cit., (1951) p 480

⁴⁶ Lasks A Grammor of Politics, (1941), p 304

गुजरने के लिए किसी पड़ की टहनी को एक तरफ हटान के बाद गाड़ी के गुजर जाने पर टहनी पून अपना स्थान व वेती है।³⁸

(3) सपरिवतनीय होन के बारण सविधान की उपक्षा करन का नाव

साधारणत जनता म जागृत नही होता।

(4) गिलकाइस्ट के अनुसार "व राप्टीय मस्तिप्त की मली प्रकार प्रति बिम्बित ररते हैं। य सविधान अतीत पर आधारित होत हैं, वतमान म सिक्य रहते हए एव मिवर्य पर दृष्टि रखते हुए शासन सम्बन्धी वतमान धारणाजा तथा सामा जिक एवं राजनीतिक स्वतात्रता सम्बाधी सिद्धा ता को अभिव्यक्त करते हैं। अ

बोप-(1) यह निरातर परिवर्तित होत रहत है अत अस्थायी एव अनिधिचत

होते हैं।

(2) राजनीतिना एव दला नी इच्छा पर इनम सरलतापूवक परिवतन होते रहते हैं। सिजविक के शब्दा म इन सविधानों में "जन विरोध के क्षणिक भोका से महत्वपूर्ण सिद्धा तो एव सस्याओं का उम्मलन हो सकता है तथा प्राचीनता एव परम्परा द्वारा प्रदत्त स्थिरता का सहज ही अंत हो जाता है।"40

(3) अलिखित सविधान लोकत त्रीय समाज की अपक्षा कुलीनत नीय समाज

के लिए अधिक उपयक्त होते हैं।

(4) अलिखित सविधान परम्पराओ एव रूढियो पर आधारित होता है। इग्लैण्ड के अलिखित सविधान का विगत 200 वर्षों मे काफी भाग लिखा गया है । टेम्परले के शब्दा में किसी देश का अलिखित सर्विवान दो कारणों से अत्यधिक खतरनाक होता है। प्रथम, रूढियों के दो अर्थ सम्मव हाते हैं जबकि कानन का केवल एक ही अथ होता है। सिद्धा तहीन एव दुस्साहसी राजनीतिनी को सबैधानिक रूढियो की इच्छानुसार व्यारया करने का अवसर सहज ही मिल जाता है। इगलैण्ड की ससद में साधारण कानून एव सर्वधानिक कानूनों में संशोधन करने की एक ही प्रक्रिया है।"

(5) असिखित सविधानों में जनता को अधिकारों का आश्वासन मही दिया जाता है तथा सावजितक कमचारियों को निषय करने की अधिक स्वता जाएत होती है। ब्राइस के अनुसार य सविधान यायाधीशों के हाथ का खिलौना होते हा 41

तिसित एव दुष्परिवतनीय सविधानो के गुण-(1) यह स्पष्ट एव सुनि

रिचत होते हैं तथा उदास राजनीतिक चेतना का परिणाम होते है।

Flexible constitutions "can be stretched or bent so as to meet 38 emergencies without breaking their framework and when the energency has passed, they slip back into their old form like a tree whose outer branches have been pulled on one side to let a vehicle pass —Lord Bryce quoted by Garner op ett, p 479 Gilchrist Principles of Political Science, (1930), p 217 39

Sidgwick The Elements of Politics, pp 561 562 40

Bryce , quoted by Garner op cat , p 480 41

- (2) इनम सावजनिक भावावेश या ससदीय निरकुशता के फलस्वरूप शीष्रता-प्रवक उग्न परिवतन या सशोधन नहीं किये जा सकते 1⁴
 - (3) यह अधिक स्थायी व स्थिर होते है।
- (4) लिखित सिवधान का निर्माण किसी समा या समिति द्वारा बहुत सोच-समऋ कर एव वाद विवाद के पश्चात किया जाता है अत उनके अथ के सम्बन्ध में अधिक मृतभेद की गजाइय नहीं होती।
- (5) लिखित सिवधानो में सामा यतया नागरिका के मौलिक अधिकारों का उन्लेख होता है। अत इन सिवधानो द्वारा नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की कहीं अधिक गारण्टी दी जाती है जिससे शासन निरक्त्व एवं अल्याचारी नहीं हो सकता।
- (6) सपीय राज्यों के लिए लिखित सविद्यान ही अधिक उपयुक्त है । सधीय सविद्यान में शासन के विभिन्न अगों के अधिकारा में सरलतापूचक परिवर्तन सम्मव नहीं होते है और न एक दूसरे के अधिकार क्षेत्रा का उल्लघन ही सरल होता है ।⁶³
- (7) लिखित सविधान म सभी व्यवस्थाएँ लिपिबड होती ह । अन किसी विपय के सुन्दम भ विवाद की स्थिति म सर्वाच्च त्यायपालिका का निणय अत्तिम होता है ।
- दोप—(1) लिखित सिविधाना का सबसे वडा दोप यह है कि वे प्राय जिटल होते हैं। समय की गति के साथ उनम परिवतन नहीं हो पाते। यह दोप एकारमक राज्यों की अपेक्षा स्थानमक राज्यों में अधिक पाया जाता है क्योंकि के प्र एव राज्यों के मध्य प्रसिन्धिमाजन के कारण अनेक समस्याएँ उत्पर्त हो जाती हैं। मैकाले के अनुसार "मातियां का एक वडा कारण यह है कि जब राष्ट्र आगे बढते जाते हैं तो सिवधान स्पिर बने रहते हैं।" वानर के अनुसार 'लिखित सविधान ऐसी गीशान की माति हैं जो व्यक्ति के आकार, विकास एवं परिवतन को ध्यान में रखे विना वनायी गयी हो।
- (2) लिखित सिवधान की ब्यारवा सरल काम नहीं है। यह दायित्व सामा-"मत "यायपालिका का सीपा गया है। यायाबीशो का इप्टिकीण साधारणतया रूडिवादी होता है। फलस्वरूप यायपालिका एक तृतीय सदन बन जाता है।" लास्की का मत है कि यायाधीश परिवर्तित युग की मावना का प्रतिनिधित्व करमे में असफत रहे हैं। वे अपेसाइत सिवधानों के निर्माण के युग की ही माबना को अमिब्यक्त करते हैं और यदि परिवर्तित परिस्थितिया के अनुरूप उनके द्वारा सविधान की ब्यास्था

⁴² Garner op cat p 478

⁴³ Laski Grammar of Politics, (1941), p 306

⁴⁵ Lasar Ordanian by Folias, (1943), p 300
44 "The great cause of revolutions is this, that while nations move onwards constitutions stand still "—Lord Macaulay, quoted by Garner op cu, (1951), p 478

⁴⁵ Written constitution "is like an attempt to fit a garment to an individual without taking into consideration its growth and size"—Garner op cit, (1951), p 480

⁴⁶ Laski A Grammar of Politics, (1941), p 304

नी जाती है तो उननी निष्पक्षता के प्रति सन्दह न्यक्त निया जाता है और उनके देतीय विवाद म फँस जान नी आसना उत्पन्न हा जाती है।

(3) विरित्त सविधान नी ब्यान्या ना अधिनार "यायपालिना का दन ना एक और दोष भी है। यायाधीदा को प्रमावित करने ने लिए उनकी निमुक्ति एवं पदच्युति करने नी दोलित ना विधानमण्डल अथवा नायपालिना कभी रती अनुवित प्रयोग नरने लगते हैं। इससे यायपालिना उनकी आधीनता म नाय नरन लगती है। इसके विपरीत, यदि सभी नियात्रण हटा लिय जात हैं तो न्यायाधीदा में पूण स्वतात हो जाने का मय होता है। '

सविधान का विकास

प्रत्येव सिव्यान अपन युग वो परिस्थितिया का प्रतिबिग्व होता है। सामाजिक अवस्था म परिवतन होते रहते हैं अत सविधाना म भी परिवतन अपित है। इस सम्बाध म अगेव प्रश्न सहज ही उत्यान होते हैं। उताहरण के लिए, क्या सामाजिक परिवतन के साथ साथ सविधान भी परिवतित होते हैं एवं वे कितनी धीम्रता स परिवत्तित होते हैं ?, परिवतन को क्या प्रणाली होनी चाहिए ?, क्या सविधान और समाज के इस्तिकोणा में गम्भीर मतभेव उत्पन्न होते हैं ? अत सविधान के विकास समाज के इस्तिकोणा में गम्भीर मतभेव उत्पन्न होते हैं ? अत सविधान के विकास समाज की किता होती है, और (2) सविधान के विकास या परिवतन के तिए कौन-सी शक्तिया उत्तरदायी होती है, और (2) सविधानों में परिवतन करें होते हैं तथा सुधीकन पा परिवतन की प्रणाली क्या है ?

सविधान के परिवतन तथा विकास के लिए मुख्य उत्तरदायी तरन, जिन्ह ह्वीयरे प्राथमिक शिवतयो (primary forces) की सज्ञा देते हैं, दो प्रकार से काय करते हैं। प्रथम, इन शक्तियों के फलस्वरूप परिस्थितयों में ऐसे परिवतन होते हैं कि सविधान में विश्वत कोई सशोजन या परिवतन होने पर मी उसके अब में गम्मीर अतर पड जाता है। द्वितीय, इन शक्तियों द्वारा ऐसी परिस्थितया उत्पन कर दी आती है कि सामाय सशोधन प्रणासी या यायिक निषय अथवा सववानिक परम्परा या असिसस्य क विकास के कारण सविधान म परिवतन हो जाता है।

ह्वीयरे ने उपरोक्त कथन के समधन में निम्न उदाहरण दिये है

(1) जीवोगिक क्रांति वे फलस्यरूप समुक्त राज्य अमेरिका के पटक राज्यों के मध्य व्यापार म अत्यधिक वृद्धि हुई यी । सविधान भेपरिवतन या सद्योधन के विना ही सधीय काग्नेस को अत्यर्राज्योग व्यापार को नियन्तित करा की व्यापक वानितवा प्राप्त हो गयी। यह शिक्त नायत न राज्यो स प्राप्त नहीं की अपितु उसे प्रारम्म से ही प्राप्त नी पर्तु उसके उपयोग का उसे उनित अवसर नहीं मिला था। अन्त राज्यीय व्यापार की शुद्धि के फलस्वरूप सथ तथा राज्या के अभित स जुलन परिवत्तित हो गये थे। एसे ही परिवतन अस्ट्रेलिया एव कनाडा में भी हुए थे।

(2) युद्ध या युद्ध की सम्भावना, आधिक सक्ट एव लोक-कल्याणकारी राज्य

⁴⁷ Sidgwick The Elements of Politics, p 564



है और उसके विचारा को सही एव उचित आदर दिया जाता है तो तीघ एय सहसा परिवतन की सम्मावना कम हो जाती है तथा परिवतन के एसे प्रयत्ना का विरोध किया जाता है। उदाहरण के लिए, समुक्त राज्य अमेरिका क सविधान का वहां को जनता श्रद्धा की इंटिए से देसती है। दूसरा चताहरण स्विस जनता का है जो अमेरिकी जनता के समान हो अपने सविधान में श्रद्धा रात्वी है। स्वास्मक राज्या में सविधान के प्रति विशेष श्रद्धा होती है, यदाप एकारमक राज्या में सविधान के प्रति विशेष श्रद्धा होती है। सपात्मक प्रति पर्याप्त श्रद्धा होती है, यदाप एकारमक राज्या में सविधान के प्रति पर्याप्त श्रद्धा होती है पर तु सथात्मक राज्यों के सहस्य नहीं। सविधाना में परिवतन के निम्म तीन साधन हैं

- (1) सशोधन प्रणाली
- (2) यायिक निणय, और
- (3) परम्पराए एव अभिसमय ।

सशोधन प्रणाली द्वारा सविधानो मे सशोधन

लिखित सविधानो म सशोधन-प्रणाली का उल्लेख होता है। सपीय एव लिखित सविधानो की सशोधन प्रणाली कठोर होती है। उदाहरणाय, सयुक्त राज्य अमेरिका, स्विटजरलैंग्ड, भारत आदि। आयुनिक सविधाना म सशोधन-प्रणाली के उल्लेख के बार मुख्य उद्देश्य निम्मवत हैं

(1) सविधान म विचारपूनक ही परिवतन किये जाने चाहिए , शीघ्रता एव

क्षणिक आवेदा म परिवत्तन वाछनीय नही है।

(2) सिवधान मे परिवतन किये जाने के पूब जनता को अपना मत ब्यक्त करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए ।

(3) सघीय सविधानी म शक्तियों के विभाजन में कोई परिवर्तन के द्र तथा

इकाइयो के परामश के अभाव मे नही किया जाना चाहिए।

(4) व्यक्तिगत या सम्प्रदाय विश्रेष के हिता के रक्षाय मापायी, सास्कृतिक

एव धार्मिक अल्पसरयको के हितो की रक्षा होनी चाहिए।

कभी तो सद्योधन के पीछे उपमुक्त सभी कारण अथवा केवल दो या तीन कारण ही सिन्य होते हैं । सिव्यान शासन का आघार है और उसका सम्मान अपेक्षित है । सर्वोधन के सम्य प ये जनता का मत ही निर्णायक होना चाहिए। यह जनप्रभुत्व के सिद्धात के अनुकूल है। जनता की इच्छा को अनेक तरीको से जात किया जाता है। कई देशों में विधानमण्डल हारा पारित मुझोधन जनता के समस विचार के तिल रहा जाता है, जसे—आयर गणराज्य, जेनसाक, आस्ट्रेलिया, स्विटजरलेण्ड, एव सभी अमेरिकी राज्यों में। विधानमण्डल को भी सखोधन करने की श्रवित्य प्रवान को जा सकती है परन्तु कई देशों में सखोधन के अतिम स्वीधन करने की श्रवित्य में सखोधन नता का मत जान तेना अवस्थक होता है। उदाहरण के लिए, वेलियम में सदोधन नता का करने के बाद विधानमण्डल के वीना स्वर विधारत हो जाते है तथा नत्वीन निर्वाचन के स्वा

बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए । डेनमान, हॉलण्ड, स्वीडन, नार्वे में भी कम वढ यही व्यवस्था है । कोलम्बिया एव इनवेडर में प्रस्ताबित सन्नोधन दो क्रमिक कांग्रेसा द्वारा स्वीकृत होना आवश्यन होता है ।

स्विटजरलैण्ड म अनिवाय जनमत-संग्रह की व्यवस्था है तथा फास के पाँचवे गुणराज्य के सुविधान के अन्तगत वैकल्पिक जनमत संग्रह की व्यवस्था है। फ्रांस में कोई रशोधन जनमत-संग्रह के लिए तभी प्रस्तुत किया जा सकता है जब वह दोना सदनो-सोनेट तथा राष्ट्रीय सभा-की सयुक्त बठक मे तीन चौथाई बहमत से पारित होता है। 13 अमरीकी राज्यों से संयोधन के सम्बाध में उपत्रम (unitiative) की व्यवस्था है। सघीय सविधाना म जासन की शक्ति केन्द्र एव राज्यों में विमाजित होती है अत दोना की स्वीकृति संशोधन को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। आस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका एव भारत म के दीय शासन के अतिरिक्त संशोधन में राज्यों की स्वी कृति भी आवश्यक होती है। सभी सघीय देशों में समान संशोधन प्रणाली नहीं है। आस्टेलिया एव स्विटजरलण्ड में संशोधन से के द्रीय एवं प्रान्तीय शासन ही सम्बन्धित नहीं होते वरन जनता की भी स्वीकृति आवश्यक होती है। मारत मे जनता का मत शात करने सम्बाधी कोई व्यवस्था नहीं है और न ऐसे किसी अभिसमय का अभी तक विकास ही हुआ है। कनाडा म 1950 ई तक के द्वीय तथा प्रातीय वासनी की एकाकी या सयुक्त रूप में सविधान में सशोधन का अधिकार नहीं था। कनाडा के सविधान में सशोधन की शक्ति 1949 ई के पूज तक जिटिश संसद में निहित थी। "विभिन्न देशो में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी अनेक तरीकों को अपनाया गया है। उदाहरण के लिए, स्विटजरलैण्ड की सशोधन प्रणाली जनप्रमत्व को स्वीकार करती है। स्विटजर लैण्ड म जमन, फ्रेच एव इतालवी राजकीय मापाएँ है। इह सबैबानिक प्रत्याभूति दी गयी है। सशोधन के अभाव में इस जबस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसी प्रकार की प्रत्यामृति कनाडा के सविधान द्वारा अग्रेजी व फा सीसी मापाओं के प्रयोग के सदम में दी गयी है।

विभिन्न सविद्यानी की समोधन प्रणालिया

प्रमुख देशों के सिवधानों की संशोधन प्रणाली का विवरण निम्नवत् है ग्रेट ग्रिटेन में टर्मिटेन में ससदीय संप्रमुता का सिद्धात भाग्य है। ससद की सिवधान में साधारण विधि प्रक्रिया के द्वारा संशोधन करने का अधिकार है। सवधानक विधि एवं साधारण विधि-प्रक्रिया में इंगलण्ड में कोई अन्तर नहीं है। जगती पिक्षियों की सुरक्षा एवं सरक्षण से सम्बंधित विधि प्रति अधिकारों को सीनित अथवा कम करने वाली विधि को पारित करने ने लिए एक ही विधि-प्रक्रिया का अनुगमन किया जाती है। इंगलण्ड की संसद द्वारा पारित सवधानिक कराने

⁴⁹ ब्रिटिश नाथ अमेरिका व्यक्तियम (1949) पारित करके धारा 91 म परिवतन किया भया है। अब ब्रिटिश सबद की कनाडा के संविधान म संशोधन नी शक्ति औनचारिक मात रह पर्द है।

धन राजा के हस्ताक्षरों हे पदवात ही प्रतावी होना है । 'यावपालिका म सतदीय विधि रो चुनीती नहीं दी जा सक्ती । स्पष्ट है कि इनलण्ड रा मविधाउ लवीला है। 1936 ई का सिहासन-स्याग अधिनियम (The Abdication Act) त्रिटिंग ससद म प्रस्तुन किये जाने व आधा घण्ट के भीतर पारित हा गया था।

ग्रेट क्रिटेन म यायालय द्वारा किसी विधि को अर्वधानिक घोषित नहीं दिया था सक्ता । वहाँ ऱ्यायिक पुनरोक्षण (judicial review) की पढति का अमाव हैं । ब्रिटेन म जो विधियाँ परम्पराओं के विरुद्ध होती हैं, उन्हें ही असवधानिक (unconsti tutional) क्हा जाता है। असन्धानिक का अय परम्परा विरुद्ध होना है। अमिसमय म परिवतन होते है अथवा यायात्तय के निसी निणय द्वारा मा सवधानिक व्यवस्था म परिवतन हो सकता है लेकिन ऐसे सभी परिवतन अनीप ग्रारिक परिप्रतन होते हैं।

संयुषत राज्य जमेरिका-अमेरिकी सविधान निर्माता एक कठार सविधान के निर्माण के लिए इच्छुक थे। सविधान के अनुच्छेद S म सत्रोधन की ब्यवस्था का उल्लेख है जो साधारण विधि प्रक्रिया से सवधा भिन्न है। समुक्त राज्य अमेरिका म सवात्मक शास : है। अत सधीय व्यवस्ता कं अनुरूप वही विगिष्ट एव कडोर सशाधन-प्रणाली का होना भी आवद्यक है।

अनुच्छेद 5 ने अनुसार "काग्रेस के दोनो सदन सशोधन प्रस्तावित करने की आवश्यकता अर्जुमव करने पर अपन दो तिहाई बहुमत से सद्योजन प्रस्तुत कर सकेंगे या विभिन्न राज्यों के दो तिहाई विधायको क आवेदन करने पर सकीधन प्रस्तान प्रस्तान बित कर । के लिए उसके द्वारा एक महासभा (Convention) बुलाई जायगी । ऐसे समी सशोधन प्रस्तावो की विभिन तीन चीयाई राज्यो द्वारा पुष्टि या इस हेतु आहत राष्ट्रीय महासमाक्षा के तीन चौथाई बहुमत द्वारा सम्पुष्टि किये जान पर ही दे प्रभावी होग । लेकिन 1808 इ के पूर्व पस्तावित किये जाने वाले संशोधनी से प्रयम अनुच्छेड के नवे वन की प्राम एव चतुर्थ धारा मे कोई परिवतन नहीं किया जा सकता और किसी राज्य को उसकी अनुमति के बिना सीनेट मे प्राप्त समान मताधिकार से विचत नहीं किया जा सकता।"

उपरोक्त अनुष्देद की भाषा से यह स्पष्ट है कि संशोधन प्रस्तावित करने एव

उसके प्रिटकरण के दा तरीके है

सशोधन के प्रस्ताव काग्रेस के दोनो सदनो के द्वारा पृथक पृथक रूप मे दो-तिहाइ बहुमत से या दो तिहाई राज्यो की व्यवस्थापिकाओ की प्राथना पर काग्रेस द्वारा आहत महासमा द्वारा प्रस्तावित किये जा सकते हैं।

प्रस्तावित सञ्चोधन को तीन चौथाई राज्यो की व्यवस्थापिकाआ या तीन चौथाई अत्याचन जना (Conventions) द्वारा सम्युष्ट (ratify) क्या जाना चाहिए। सम्पूर्त्य के बन दो तरीनों म से कीन सा तरीका प्रयोग म लाया जाय, इसका निणय करने का अधिकार काग्रेस को है। अत ने लिए कप्रिस द्वारा निर्धारित रीति का ही प्रयोग किया

उपर्यक्त दो तरीको में से अमेरिकी सविधान के समी मशोधना के लिए काँग्रेस के दोना सदनो के दो तिहाई बहुमत द्वारा प्रस्तावित एव तीन-चौथाई राज्या की न्यवस्थापिकाओ द्वारा सम्पृष्टिकरण की रीति को ही मुख्यत अपनाया गया है। इसका केवल एक ही अपवाद है। मद्य निपंघ की व्यवस्था को समाप्त करने वाला 21वां संशो-धन राज्या की महासभाओं द्वारा सम्प्रष्ट किया गया था।

समक्त राज्य अमेरिका के सर्विधान में अभी तक 25 संशोधन हो चके हैं। प्रथम 10 संशोधना की 1791 ई मं सम्पृष्टि की गयी थी। 18व तथा 21वें संशाधना का सम्बाध मद्यानिवेध से है। 18वें सञ्चाबन के द्वारा मद्यानिवेध लाग किया गया और 21वें सशोधन के द्वारा उसे समाप्त किया गया था।

अमरिकी सविधान की संशोधन-प्रणाली की सामा य आलोचना निम्नवत है

- (1) संशोधन प्रणाली जटिल एवं कठोर है।
- (2) सदोधन से सम्बन्धित अनुच्छेद म निम्नलिखित बातो को स्पष्ट नही किया गया है ---
- (1) दानो सदना के दा तिहाई बहुमत का क्या अथ है ?--ससद के कुल सदस्यो का दो तिहाई बहुमत या उपस्थित सदस्यों का दो तिहाई बहुमत । व्यवहार म उप-स्थित सदस्या के दो तिहाई बहुमत को ही मा यता दी गयी है।
- (n) सविधान इस सम्बाध में मौन है कि संशोधन प्रस्तावित करने के लिए राष्ट्रपति की जनुमति की आवश्यकता है या नहीं ? सर्वोच्च यायालय ने इस सम्बाध म निणय देते हुए कहा है कि संशोधन विधायी प्रक्रिया है अब उसे राज्या के पास अनुसमयन के लिए भेजने स पून उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। 81
- (m) सवितान ने राज्यो द्वारा सवैधानिक सञ्चाधन की पृष्टि के लिए निश्चित समय निर्धारित नहीं किया है। पर तु काग्रेस को अनुसमयन का समय निर्धारित करने का अधिकार है। कायस ने 18वे, 20वे तथा 21वे संशोधना के अनुसमयन पा सम्पुष्टि के लिए अधिकतम 7 वप का समय निश्चित किया था।
- (IV) अनुच्छेद 5 की मापा से यह भी स्पष्ट नही है कि किसी राज्य की ध्यवस्थापिका एक बार सञ्चाधा की पुष्टि करने के पश्चात लेकिन तीन चौथाई राज्यो की व्यवस्थापिकाजा द्वारा पुष्टि के पूर्व अपन सम्पुष्टि (ratification) सम्बंधी निणय को बापस ले सकती है या नहीं ? काग्रस न प्रस्तान पारित करके यह घोषित विया है कि राज्य ऐमा नहीं कर सकते । लेकिन संशोधन को एक बार मम्पुष्ट न करन पर उस बाद म फिर मम्पूप्ट वरने का अधिकार राज्या को है।
 - (v) एक विवादास्पद प्रश्न यह भी है कि क्या किसी राज्य की ब्यवस्थापिका

Refer to Ogg and Ray Essentials of American Government, (9th 50 edn , 1964), pp 31 33

⁵¹ Ogg and Ray op cit, p 31

न्युमारधा ने हुनु प्रशाहित ग्रामात ना जाता ना ग्राहित हुनु प्राप्त्या कर प्रशा रे या पक्ष रे दम सम्ब च म मामा र मत यह है जि न्याम्पाधिक नामा प्रति स्व परियाग पहीं नर सनतो। उस ॥ प्रधा पर बतात प्राप्त नरत ना अधिकार हैपस्तु यह निम्म स्थिय हुनु मथ्यातिन है प्रभाव ना नतात न सम्बन्ध न्युत प्रशास मस्त्री। प

यह जीनम रिषय हुई मध्यारिक ६ तथात्र वा बत्तात्र कमार ब्लाइत रहेत्त्र रहेत्त्र पहाती." सविपात के जुमार सनाच ता बी पुष्टि राज्या द्वारा की जाना काहिए व हि जाता के द्वारा । यह सनुका राज्य जबस्थित व 13 राज्य किन जाव साथ बढ़े

हि जाता ने उत्तर । यदि सनुसन राज्य अमितना न 13 राज्य निन जाय तो व गर्दू मत मी इन्द्रा का विष्यमा है वर मन १ है । अब सामान प्रणाता प्रीतिकारणी है। विषय में का तिहाई बहुम र एय तीन भोभाइ राज्या की स्वयस्ताविकामा इति

सम्पाद सम्बन्धी स्ववस्थार्ष वहुमत है वाल प्राथा स्वास्था मन्यस्थार्थ कार्यस्था स्ववस्थार्थ वहुमत है। त्या के स्वास्था स्वास्य स्वास्था स्

राज्या द्वारा सर्वपानिक मनापन के अनुनामधन र लिए काई निव्यत अवधि निर्मातित नहा है। उदाहरण के लिए, जाजिया, भ्रवेण्युस्टस एव आहिया राज्या न प्रयम दस सर्वोपना का 1934 ई म सम्युट्ट क्या था। एक जन्य सर्वोपनकी राज्युट्ट करने म भोहियो राज्य ने 80 वयं का समय सिया। 1924 ई म बास-धम सम्यन्धी सर्वापन कांग्रेस ने पारित क्या था। 1936 ई तक उसे केवल 28 राज्यों ने सम्युट्ट क्या था।

सबयानिय सत्तोपना वो महासमाक्षा (Conventions) की व्यवसा वियानमण्डल के समक्ष अनुसमयन हुतु प्रस्तुत करना बुद्ध आत्तोचका की इटिट में अलोक्ता मिक है। जनना तम है कि व्यवस्थापिकाओं में प्रतिनिधिया की सक्ष्या व्यवसाहक कम होती है और वे सत्तोधना की स्वीहति वा सम्युट्टि की नयी थी। उस समय एस प्रतीत हुआ था कि नवीन परम्परा की स्यापना हो। रही है लिकन 22व सरोधन को, जो राष्ट्रपति के पदावधिक्याल से सम्यप्ता था, राज्यों को व्यवस्थापिकाओं हारा ही सम्युट्ट किया गया था। प्रधा देव स्वाधिक तो अविरित्त स्विधान का मूल माग है। वर्जनिया, "प्रयाक एवं सेकच्युत्रह्म राज्यों ने सविधान को तमी स्वीयन रिक्या था जव उह यह वाववातन दे दिया नया था कि अमेरिकी सविधान में अधिकार किया प्रविचार को साम व्यवस्था होरा हो समुद्ध के वावधिक से से से वी सो स्वीयन से थे। दो सरोधन मय विधिय से सम्याधित हैं। अब 181 वर्षों म अमेरिकी सविधान म व्यवहारिक हुए से के बन्दि शि स्वीधन हुए हैं। निपारित सरोधन पद्धित सुहोन वाले स्वीधनों की यह सरया नमण्य है विकल अनेपचारिक रूप म—न्याधिक प्रकृत्या व्यावस्थित हैं। उस 181 देवें रहे हैं।

1 1/2

⁵² Ogg and Ray op at, p 33 53 Ibid, pp 33 34

स्विटजरलण्ड—स्विटजरलण्ड का सविधान कठोर या दुष्परिवतनीय है। 1874 ई के सविधान के तृतीय अध्याय म सवधानिक सशोधन प्रणाली का उल्लेख है। सविधान म पूण एव जाशिक सशोधन की व्यवस्था है। पूण सशोधन 1874 ई मे हुआ था। स्विटजरलण्ड का सविधान अमेरिकी सविधान से कम कठोर है। 1848 ई से 1974 ई तक स्विटजरलण्ड के सविधान में 57 आशिक सशोधन हो चुके है।

स्यिटजरलैण्ड मे फेडरल असेम्बली के दोनो सदना द्वारा सशोधन स्वीकृत होने और केन्टनो के बहुमत अयदा नापरिकां के बहुमत द्वारा स्वीकृत होने पर स्विस सिवधान में पूण एवं आशिक संशोधन किया जा सकता है। फेडरल असेम्बली का यदि एक सदन संशोधन की स्वीकृत और दूसरा सदन अस्पीकृत करता है तो संशोधन प्रस्ताव जनता के समक्ष स्वीकृत के लिए प्रस्तुत किया जाता है। जनता के बहुमत द्वारा संशोधन के पक्ष में मत दिये जाने पर फेडरल असेम्बली के नये चुनाव होते हैं। नव निवाजित फेडरल असेम्बली के नये चुनाव होते हैं। नव निवाजित फेडरल असेम्बली के नये चुनाव होते हैं। नव निवाजित फेडरल असेम्बली के नये चुनाव होते हैं। कि लिए प्रस्तुत किया जाता है। दोना सदनो द्वारा स्वीकृत कर तिये जाने पर संशोधन प्रस्ताव के दिनो तथा जनता के समक्ष अनम्बत के लिए प्रस्तुत किया जाता है और केटनो एवं जनता के बहुमत द्वारा स्वीकृत किये जाने पर संशोधन पारित माना जाता है तथा सविदान का अग वम जाता है।

हिनस जनता को सदाधन प्रस्ताबित करने का भी अधिकार दिया गया है । 50,000 स्विस नागरिक हस्ताक्षरो सिहत सबोधन प्रस्तावित कर सकते हैं। प्रस्तावित सदाधन पर जनमत लिया जाता है और वहुमत द्वारा समिवत होने पर नवीन चुनाव होते हैं। प्रस्तावित सबोधन नविनवीचित फेडरल असेम्बती के समक्ष स्वीकृति हेंतु रखा जाता है। फेडरल असेम्बती के द्वारा स्वीहत होने पर केटनो एव जनता का मत नात करने हेंतु जनमत सबह होता है। बोना के द्वारा बहुमत से स्वीकृत होने पर सवीधन माय होता है।

गाधिक सबैधानिक मधोधन को प्रस्ताबित करने के लिए उपकम (Initiative) की भी व्यवस्था है। इसकी दो प्रणालियों है—(1) मतदाता सर्वोधन की मोग का प्रस्ताब कर सकते हैं। और (2) वे सर्वोधन का प्रस्ताव करते समय उसका प्रारूप भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अप प्रथम प्रकार को अनिमित उपकम (Unformulated Initiative) कहते हैं। इसरे प्रकार ज्यांत मतदाता आ द्वारा संवोधन के प्रारूप को प्रस्तुत करने भी रिति को निमित उपकम (Formulated Initiative) कहते हैं। सरोधन के अनिमित उपमम की फेडरल असेम्बली द्वारा स्वीकार कर तेने पर सरोधन प्रस्ताव का निर्माण करके उसे जनता एव के टना के समझ जनमत-स्वग्रह ने लिए प्रस्तुत विया जाता है। यदि फेडरल असेम्बली क्रांगित सरोधन का अस्वीकृत कर देवी है तो जनता की राय इस प्रस्त पर लिय जान का जाम का विधान है कि आधिक सरोधन हो अवया नही। यदि जनता द्वारा आगिक सरोधन के स्वीवृति दी जाती है तो स्वाधिन का प्रारूप पेडरल असेम्बली द्वारा वेटना एव जनता के स्वावृति वेटी जाती है तो स्वीधन का प्रारूप पेडरल असेम्बली द्वारा वेटना एव जनता के समझ स्वीकृति हत्य रचा जाता है।

निर्मित संगोजन प्रस्तानां (Formulated proposals for amendments) को फेडरल जसम्बसी पहले स्वीरृति प्रमान नस्ती है और उसव बाद व नहना तथा जनता ने समक्ष जनमत सग्रह ने लिए प्रस्तुत किय जात हैं। पंडरल असम्बती बिर्मित समीपन के प्राच्य नो स्वीरान नहीं करती वो उसे जनता से समक्ष प्रस्तुत नरक अस्वीरृत नरत में यौय नरते या सदागरा प्रस्ताव के साथ नयीन प्रस्ताव ना निर्मित करके जनता के समक्ष प्रस्तुत ने समक्ष प्रस्तुत ने निर्मित करता के समक्ष प्रस्तुत ने समक्ष प्रस्तुत ने निर्मित करता के समक्ष स्वीरृति वे लिए प्रस्तुत नरन वा अधिकार है।

रिश्स सशापन प्रणाली से यह स्वप्ट है कि सशापन प्रस्तावित करने का अधिकार तीनो—जनता, सथ को परिपद (कायपासिका) एव फेडरल असम्यली—को है लेकिन प्रायेक अवस्था म सरोधन प्रस्ताव अनतागत्या जनता द्वारा ही स्वीटत होना चाहिए। फाइनर¹¹ के अनुसार इस प्रकार की सरोधन प्रणाली के निम्न प्रमाव हात हैं

प्रथम, स्विस सविधान म सामाय विधि प्रक्रिया की तुलना म सरोधन प्रणाली के स्विचा महत्व प्रवान के सामाय विधि प्रक्रिया की तुलना म सरोधन प्रणाली के सिव्य महत्व प्रवान विधा गया है। स्विस सविधान म सामाय विधि-निर्माण के सम्बाध म जनमत-सग्रह की येवल वकत्वित व्यवस्था है जविक सवधानिक सरोधन के लिए अनिवाय जनमत सग्रह की व्यवस्था की गयी है। द्वितीय, स्विस सविधान म जनता को सविधान प्रस्तावित करने का भी अधिकार प्रयान किया गया है। 50 हजार गागरिक स्विद्या जनात का 80वी हिस्सा है। यातायात क आधुनिक साधामों को देखते हुए इस सब्या की सगरिव करना करित नहीं है। अत सविधान की विद्याप स्थिति के बारे म जनता का विचार विभाव का अवसर दिया गया है। इस व्यवस्था से सविधान म परिवतन सरततापुत्रक सन्मव है। 1874 ई क बाद 14 बार जनता हारा सिधान में सक्षीयन प्रस्तावित क्यि गये है। इनमें के केवल 5 स्वीकार किये गये हैं। इसी काल म फेडरल अमेनवती द्वारा 30 सक्षीयन स्वीकृति हेंचु जनता के सामने रखे गये थे, जिनमे से 24 स्वीकृत हुए है। सत्तीधन की यह पद्धित स्वरूप स्वाम म सफल रही है।

संयुक्त राज्य अमेरिका जब आस्ट्रेलिया की तुलना में स्विम सविधान की सबी धन व्यवस्था कठोर नहीं है। 1874 से 1944 ई तक स्विटजरलज्ड म 83 सवैधा निक जनमत सम्रह हुए है। फेडरल असम्बली हाग 41 प्रस्तान जनता के समझ स्वी इति हेतु रखे गय जिनमें से 34 स्वीड्टत हुए हैं। जनता हारा 35 प्रस्ताव उपस्थित किये गये थे जिनमें से केवल 7 प्रस्ताव जनमत सम्रह वे बाद स्वीकृत हुए है।

विभिन्न आधिक संयोजनो द्वारा स्थित सर्वेधानिक व्यवस्था म बहुत कम परिवतन हुए हैं। इनम से अधिकाश संशोधनों ने व्यापार एवं वाणिष्य सम्बनी स्वतंत्रता को सीमित करके केन्द्रीय शासन को शक्तियों में वृद्धि की है।

स्विस सविधान की एक अनिवाय विश्वेषता यह है कि सविधान म परिवर्ग संशोधन प्रणाली द्वारा ही सम्मव है। यायिक निणयो एव नजीरो (Precedents) र

54 Finer H op cit, pp 133 134

द्वारा सविधान का विकास मही हुआ है। स्विस प्रणाली म यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था का पूण अभाव है। स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल फेडरल असेम्बली द्वारा पारित किसी भी विधि को अवध घोषित नहीं कर सकता। स्विस जनता इस सिद्धान्त म विश्वास करती है कि सप्रभुत्व शक्ति जनता या व्यवस्थापिका या उसके प्रतिनिधियों के हाथा म रहनी चाहिए। हास हुबर का कथन है कि "स्विस जनता का यह विश्वास है कि सवधानिक विधि की याथिक व्यारया का अथ लोकत त्रीय धिद्धा तो का अति कृमण है।

सोवियत रूस (The Union of Socialist Soviet Republic)—सोवियत रूस के 1936 ई के स्टालिन सविधान के अनुष्टेंद 146 में संवोधन प्रणाली का उत्सेदर हैं। सुप्रीम सोवियत के दोना सदनो अर्थात सोवियत ऑफ प्रूनियन एव सोवियत ऑफ नैदानिटिंग द्वारा पृथक पृथक रूप के अपने दो तिहाई बहुमत से संवोधन पारित होने पर सिवयन म परिवतन किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, प्रेसोडियम, यि परिपद (Council of Ministers) और यहां तक िक श्रम एव सुरक्षा समिति (Council of Labour and Defence) के द्वारा भी सिष्धान में महत्वपूण परिवतन किये जाते हैं। उदाहरण के लिए, 1946 ई म प्रेसीडियम के एक आवश्य के द्वारा सुरक्षा कंजन कमीसार (Peoples' Commissariat for Defence of USSR) को सख की सक्षस्य सेमा के मण्यालय म बदल दिवा गया था तथा नम, जल एव स्थल सेना का एकोकरण कर दिया गया था।

1936 ई म सिवान के लागू होने के पश्चात 20 वर्षों मे 23 सशीयन पारित ही चुके हु । 1944 ई मे सघ की मुस्य इकाइयो—सधीय गणराज्यो (Union Republics)—को सुरक्षा एव वैदेशिक मामलो म पुण्क अधिकार दिये गये हैं एव काउसिल ऑक पीपुल्स कमीसार को मिनमण्डल (Council of Ministers) की सचा दो गयी है। दितीय विश्व मुद्ध के बाद सघ म नये राज्यो को भी शामिल किया गया है।

क्स के सिवधान की सघोधन प्रणाली मामा य विधि प्रत्रिया से मिन्न है। अत उसको कठोर सिवधान की सजा दी जानी चाहिए। लेकिन अमेरिका, स्विटजरलण्ड आदि सघीध दशा की सदो न प्रणासी की तुलना में बहु कम कठोर है परन्तु दुगलण्ड की सदोधन प्रणाली से कठोर है। सोवियत रूस में सदानिन सम्ब घी प्रस्तात गुप्रीम सोवियत के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। सोवियत स्म सप की इचाइया को अमेरिकी राज्या भी तरह सदाधान प्रस्तावित करने का अधकार नहीं हैं। सरणीय है कि रूस की मौति ही स्विटजरलण्ड म वेंटना की भी सदाधन प्रस्तावित करने ना अधिकार नहीं है। न रूस में जमेरिकी राज्या की तरह सम वी इकाइया द्वारा सप्तीयन की पुष्टि की आवस्यनता है। सावियत रूस की सदीधन प्रणाली एकात्मक राज्या स

⁵⁵ Hans Huber How Switzerland is Governed, (1946), p 10

मिलती है ग्योबि सतोधन प्रस्तावित करन एव उन्ह सम्युष्ट करन के बार म सम भी इकाइयो को काई अधिकार नहीं हैं।

सुप्रीम सावियत म साम्यवादी दल का एकाधिनार हान के कारण सशोधन क

लिए आवश्यक दो तिहाई बहुमत सहज ही उपलब्ध हा जाता है।

भारत—मारतीय गणराज्य का सविधान सदीधन प्रणाली की हिन्द स बठीर एवं लचीला दोना हो है। हजलब्द के सविधान की भांति भारतीय ससद सामाय विधि की प्रक्रिया के अनुसार सरस्तापुषक सदीधन नहीं कर सबती और न समुक्त राज्य अमेरिका की भांति सदीधन की प्रणाली जटिल ही है। सविधान निर्माताओं ने मध्य-भाग का अनुसरण किया है।

अनुच्छेद 368 के अनुसार सबीधन विषेयक ससद क दोना सदनो द्वारा पृथक पृथक रूप में अपनी कुल सदस्य सरूपा के बहुमत एवं उपस्थित सदस्य के दो तिहाई बहुमत से सिद पारित किया जाता है और राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है तो सद्दावन मा य होता है।

यदि सात्रोधन का प्रयोजन सविधान के निम्नलिखित उपबंधों में परिवतन करना है तो ससद द्वारा उपरोक्त रीति से प्रस्ताव के पारित होने और राष्ट्रपति के समझ हस्ताधर हेतु प्रस्तुत किये जाने से पूब कम से कम आधे राज्यों की व्यवस्था-पिकाओ द्वारा उसका अनुमोदन आवस्यक होता है

(1) राष्ट्रपति का निर्वाचन एव निर्वाचन-पदित (अनुक्छेद 54 एव 55)।

(2) सम की कायपालिका शक्ति (अनुच्छेद 73)।

(3) राज्यो की नायपासिका शक्ति (अनुष्येद 162)।

(4) सधीय क्षेत्रा म उच्च यायालय (अमुच्छेद 241) ।

(5) सधीय यायपालिका (अध्याय 4, माग 5)।

(6) राज्या के उच्च यायालय (अध्याय 5, भाग 6)।

(7) विद्यायी सम्ब व (भाग 11 का प्रथम अध्याय) ।

(8) विधायी सूचिया ।

11.

(9) राज्यो को ससद मे प्राप्त प्रतिनिधित्व।

(10) अनुञ्छेद 368—संयोधन-प्रणाली ।

भारतीय सविवान की उपरोक्त संशोधन पदांति संधीय सिद्धा त क अनुरूप है। संधीय संसद वो संविधान द्वारा प्रदत्त छात्तियों म परिवतन का अधिकार नहीं है। ऐसा यह भारतीय संप वी 1/2 घटक इकाइयां—राज्या—की व्यवस्थापिकाशा की सहमिति से ही कर सनती है। जो अमर न बी का मत है कि यदि के द्व को विना राज्यों की सह प्रति के सिक्ता की सूची म परिवर्तन का अधिकार होता है तो चह संधीय सिद्धात के अनुरूप नहीं है। ऐसी दियति म के द्व धक्तिशाली हो जाता और सरलतापुत्रक राज्यों की स्वापस्तत को भव कर सन्तिया या। स्विधान द्वारा के द्व को प्रदत्त सकटकालीन सिक्ता हो हो। सुत्र सुदत्त सुदत्त सकटकालीन सिक्ता एव कुछ अय उपवष्य संधीय स्वरूप के अनुरूप नहीं है और मारतीय संघ

MIMMAIL LIFE

विश्व के अय सपीय सविधाना जैसे आस्ट्रेलिया एव सयुक्त राज्य जमेरिका से भिन वना देते हैं।56

Ŋ, ð

उपरोक्त अनुच्छेद म सविधान के संशोधन की दो विधियों का उल्लेख है। प्रथम, ससद की अपने कुल नदस्या के दो निहाई बहुमत एव उपस्थित सदस्या के स्पप्ट बहमत स संशोधन का अधिकार है । द्वितीय, अनुच्छेद म उल्लिखित विषयो म संशाधन के लिए ! राज्या भी व्यवस्थापिकाओं का समयन आवश्यक है। इसके वितरिक्त एक तीसरा तरीका भी है। कुछ मामला म ससद सविधान में साधारण विधि प्रक्रिया की मौति सरलतापुरक संगाधन कर सकती है, यथा--राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा एवं नाम म परिवतन (जनुकदेद 4 (2)], राज्या की व्यवस्थापिकाओं के अच्च सदन--विधान परिपद्--का निर्माण या विघटन [अनुन्छेद 169 (3)] एव परिगणित जातिया व क्षेत्रा सम्ब भी उपबन्धा [5वा एव 6ठा परिशिष्ट] म ससद साधारण विधि द्वारा संशोधन कर सकती है।

3ांo के की राव⁵⁷ एक चीचे प्रकार का और उस्लेख किया है। मविधान मे कुछ ऐसे निम्नलिखित उपवाध हैं जो सबधानिक महत्व के है और जिन्हे फान्सीसी मावयवी या आधार नन विधि (organic law) नी सज्ञा देते हैं। यथा---

निवाचन क्षेत्रा का परिसीयन (अन्० 81). निर्वाचन सम्बंधी विधियाँ (अनु० 327), केन्द्र प्रशासित क्षेत्री का गठन (अन्० 240),

परिगणित क्षेत्रो एव जातिया का प्रशासन (5वीं एव 6ठवा परिशिष्ट)।

स्मरणीय है कि सबधानिक समोधन प्रणाली पर सविधान समा न अत म विचार किया था और अस्य त शोधतापुर्वक सदन ने इस निवटा दिया था। सभी सदस्य जल्दी मे थे। जल डॉ॰ राम का मत है कि सद्योधन-प्रणाली मे अनेक कमिया रह गयी है जिन्ह यायपालिका को दूर करना पहेगा। उदाहरण के लिए---

(1) राज्या की इच्छा जानने की पद्धति या रीति क्या है ? मारतीय सर्विधान में संयुक्त राज्य अमेरिका की माति राज्यों को अपनी इच्छा व्यक्त करने के सम्बाध म एक निश्चित अवधि का प्राविधान नहीं है। एक प्रश्न यह भी है कि क्या सशोधन सभी राज्यों के विधायका का भेजना आवश्यक है या कछ राज्यों के विधायका को नेजना ही पर्याप्त होगा ? स्मरणीय है कि ततीय सवधानिक सद्योधन आवे राज्यो द्वारा स्वीकृत होने पर ही पारित घोषित वर दिया गया था जब कि उस समय कुछ राज्या म उस पर विचार विमश ही चल रहा था। मसूर सरकार न इस पद्धति पर वडी आपत्ति भी नी थी। यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्यों ने विधानमण्डल की माति भारतीय राज्या के विधानमण्डल स्थायी नहीं हैं। वे

Amar Nand: The Constitution of India, 1962, p 291
 Rao, K V Parliamentary Democracy of India (1961), pp 298-300

कभी भी स्थिगत या विषटित हा सकत है। यह भी क्षम्मव है कि राज्य व्यवस्थापित के उच्च सदन द्वारा पारित या अस्वीकृत संशोधन प्रस्ताव राज्य विदानमण्डत द्वारा पारित प्रस्ताव मान लिया जाये।

(2) एक प्रस्त यह भी है कि क्या के द्व को सञ्चायन वियेयक को किसी भी समय वापस लेंगे का अधिकार है ? यह बका इसलिए उठती है कि राज्यो द्वारा स्वी कृति प्रदान करने के लिए सयुक्त राज्य अमेरिका की भाति यहा कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं है। यह सम्भव है कि इसी बीच परिस्थितिया यदन जामें अथवा के द्वीय शासन वियेयक को वापस लेना चाहे।

(3) क्या कोई राज्य एक बार व्यक्त अपने मत को बदल सकता है ? संयुक्त राज्य अमेरिका म तो राज्य द्वारा एक बार अभिव्यक्त मत को बदला नहीं जा सकता। हा, यह ध्यतस्था अवस्य है कि यदि राज्य ने सज्ञाधा-प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान नहीं की है तो वह जसे पुन स्वीकृत कर सकता है (Chandler v Wise, 1939) 88।

(4) सुविधान को किस तिथि से प्रमाबी माना जाना चाहिए ? जिन क्षण से राप्ट्रपति अपने हस्ताक्षर प्रदान करता है या संबोधन गजट में प्रकाशित होता है या राप्ट्रपति जिस तिथि से उसे लागू करने की धोषणा करता है।

(5) क्या राष्ट्रपति सशोधन विवेषक पर हस्ताक्षर करना अस्वीकृत कर

सक्ता है ? सर्वोच्च 'यायानय न शकरीप्रसाद बनाम भारतीय सच (1951) नामक विवाद में सुविधाल में सदीधन-विवेचक के सम्ब थे म निम्मलिखित बाते निरिचत की है

(अ) सबैधानिक सदोधन-पद्धित विधायी प्रक्रिया है।
(आ) सदोधन विधयक के सादभ में जहा तक सम्मय हो, जनुन्छेद 118 के

आधीन सप्तदीय नियमो का पालन होना चाहिए।
(इ) सबधानिक संशोधन विषेषक साधारण विवि की माति सप्तद द्वारा पारित

(इ) सवधानिक संशोधन विध्यक साधारण विविका भारत संसद द्वारा पारित किया जा सकता है।

(ई) अनुच्छेद 368 एक पूण सहिता नही है।

(ज) भारतीय सविधान म सशोधन का अधिकार किसी सविधान सभा को न देकर सतद को दिया गया है एव विधेष वहुमत का प्राविधान केवल प्रक्रिया सम्ब धी व्यवस्था है।

(क) माग तीन (मीलिक अधिनारो) में भी संशोबन किया जा सकता है। के बी राज के अनुसार भारतीय सिल्यान मल ही कठोर प्रतीत होता है। परातु जिस हरिट से वह निर्मित है उस हरिट से कठोर नहीं है। उदाहरण के लिए, मीलिक सीधनारों में संशोधन परस्तापुषक सम्मत है। लचीला सीधनान एन अल्य सम्यका के लिए मीलिक अधिनारा की अवस्था एक साथ नहां चल सकते। यि अल्यसस्यकों को निरतर बहुसस्यका नी हुपा पर रहना है तो लिखित सिव्यान एवं

58 (1939) 307 U S 474, cated by K V Rao of cit p 300

रद्दी कागज के टुकडे से अधिक नहीं है । डा॰ राव के अनुसार मौलिक अधिकारा म सबोधन का अधिकार तब तक नहीं होना चाहिए जब तक सभी के द्वारा उसकी सहमति न दी गयी हो । ⁹

संघीय दृष्टि से देवा जाय तो अनेक सर्वधानिक महत्व के विषया मे मारतीय ससद साधारण बहुमत स सक्षोबन कर सकती है, जैसे—निर्वाचन क्षेत्रों का सीमाकन, केंद्र प्रसासित सेत्रों को ससद में प्रतिनिधित्व एवं संघ की इकाई के रूप में राज्यों का अस्तित्व केंद्र वी इच्छा पर निमर है। केंद्र राज्यों की सीमा, आवार आदि में स्वेच्छा से परिवतन कर सकता है। स्पष्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की माति राज्यों की स्थिति स्वायों एवं सुनिश्चित नहीं है।

के वो राव ने सिवधान की सवाधन प्रणाली के सम्बाध में अस तोप व्यक्त करते हुए सुफाव दिया है कि सबैधानिक सशोधन की व्यवस्था यदि प्रत्यक्ष रूप से सम्बान न हा तो अप्रत्यक्ष रिति से ही बिसी न किसी प्रकार जनता से सम्बाधित होनी चाहिए। वे जनमत समृह की व्यवस्था का ममयन नहीं करते और उमे व्यथ एव हानिकारक भी मानत है। वे इगलैण्ड म प्रविक्ति व्यवस्था को स्वीकार करन ने पश्चाती है अर्थात जब कभी कोई गम्मीर सबोधन प्रस्तावित किया जाय तो लाकसमा नो विध-दित करक नवीन निर्वाचन कराये जायें। इस सम्बाधन में एव व्यवस्था को स्थापना की स्थापना की सा सकती है। राष्ट्रपति को प्रत्येक महत्वपुण सबैधानक सशोधन को अपनी स्थीइति तमी प्रदान करानी चाहिए जब उसे यह विस्वास हो जाम कि राष्ट्र उसने पश्च में है एव इस सम्बाध म निवाचन के माध्यम से राष्ट्र अपनी सम्मति अभिव्यक्त कर चुका है।

मारतीय सिवतान के सम्ब ध में यह भी कहा जाता है कि अति धीझतापूचक उसमें परिवतन हुए है। विमत 23 वर्षों म 32 संधोधन हो चुने है। इसका कारण यह तब्द है कि इन वर्षों में केंद्र म काग्रेस दल का स्पष्ट बहुमत रहा है और अधिक तर राज्या में अधिकास समय में काग्रेस हो सत्तास्त्र रही है। पर जुसविधान म सप्तो- मनो को जिन परिस्तित्यों म पारित किया गया है उनकी समीक्षा करने पर हमारे समक्ष एक पिन चिन्न उपस्थित होता है।

मीलिक अधिकारों से सम्बंधित पाच संघोजन है—प्रथम (1951), चतुन्न (1955), 16वा (1963), 17वा (1964) एव 25वा (1971)। यह विश्वेष परि रियतियों में पारित किय गये थे। जमीदारी उम्मूलन की विधिया की वैधानिकता की मुनीती दिये जाने पर प्रथम संघोधन द्वारा सम्पत्ति सम्बंधी अधिकार म 31 (ज) तथा 31 (ब) दो अप अनुच्छेद जोडकर इन विश्विमों को मान्यता प्रदान की गयी। अनुच्छेद 15 एवं 16 (6) में भी संघोधन किये गया। 16वें संघोजन द्वारा राज्या की अनुच्छेद 19 के जनगत विचार एवं अनिव्यक्ति की स्वतं नता पर जिंवत प्रतिप्रभ लगाने का अधिकार दिया गया। 17वें संघोषन द्वारा अनुच्छेद 31 (ज) में उल्लिखित 'estate' शहर की पुनन्यात्वा की गयी। स्मरणीय है कि विसन्न राज्यों ने इस सहर की निन्न-भिन्न व्यारवाएँ की थी और यायालय द्वारा भूमि सुधार सम्बची अनुच्छेद 31 (अ) के आवीन निमित राज्यों की अनेक विधियों को अनुच्छेद 14, 19 एवं 51 का अविक्रमण करने वाली विश्विया मानकर अवैधानिक घोषित कर दिया गया था। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 (अ) में उल्लिखित 'cstate' शब्द के अन्तगत रहत बाडी व दोवस्त एवं अप प्रकार की भूमि को भी शामिल कर दिया गया। यह मंधी धन 26 जनवरी, 1950 से प्रमावकारी उहराया गया। इस संशोधन द्वारा यह मी व्यवस्था की गयी थी कि निर्धारित सीमा में भूमि या उस्त पर निर्मित समन अधि की शासन उस समय तक हस्तगत नहीं कर सकता जब तक कि सम्बध्य ति बिष्ठ द्वारा वारा मूमि

लय मे चुनौती नहीं दी जा सकती।

24के सर्वोधन (1971) के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ससद को
मीलिक विध्वनारी सहित सिवधान के सभी मागो को स्वोधित करने का अधिकार है एवं

यह मी स्पष्ट कर दिया गया है वि राष्ट्रपति के लिए ऐसे विधेयक को स्वोधित करने अनिवाय है। इस सर्वोधन को पारित करने की आवश्यकता गोलकनाथ विवाद (1967)

में सर्वोच्च पायालय द्वारा दिये गये निष्य से उत्पन्न हुई थी। इस निष्य के परिणाम-स्वक्ष्म सस्व को मीलिक अधिकारा की सर्वोधित करने का विध्वार समस्त हो गया या। इस विवाद म सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पुत्र हिन्दिकोण के विपरीत अस्पबहुमत से सुपरोक्त निष्य किया था। स्मरणीय है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वा है दिवारी

सुधार सम्ब वी राज्या की 44 अप विभिन्ना को नवे परिशिष्ट म शामिल कर दिया गया। इस प्रकार, इन विभिन्ना को किसी सचेह या अभिश्वितता के आधार पर पाया

चयन एव सविधान की प्रस्तावना म निहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मौलिक अधि-नारा को सामाजिक हित में सीमित करना आवस्यक हो सकता है। सन् 1971 का 25वा संदोधन भी मौलिक अधिकारा से सम्बद्धित है। इस

सन् 1971 का 25वा संगोधन सी मीतिक अधिकारा से सम्बंधित है। इस संघोधन के द्वारा ()) सावजीवन उद्देश्य के लिए हस्तगत की गयी सम्पत्ति नी क्षतिपूर्ति निर्वारित करने का अधिकार ससद का दिया गया, तथा (॥) अनुरुद्धद 39 (ब) एव (स) म निहित निर्देशक तत्वा के क्रियानयम हेतु निर्मत विधिया को सरक्षण प्रदान वियागया। इस दृष्टि से सविधान म एक नया अनुरुद्धि— न्यु 31 (म)— जोड़ा गया और राज्य के नीति निर्देशक तत्वा को क्रियानित करने हतु निर्मत विधिया को न्याया लय में क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। ऐसी विधिया को नम्यत्ति सम्बन्धी अधि वार के जीतिप्रमण न बानार पर न्यायालय म चुनौती नहीं दी जा सकती। 32व संशायन के द्वारा करत राज्य के दी मूर्मि सुधार सम्बन्धी अधिनियमा ने न्यायालय के सीनारितर से सरक्षण प्रदान निया गया।

कुछ सदोषन व्यावहारिक कठिनादया ना दूर करने क लिए किये गये है, जस-दितीय मनाधन (1952) द्वारा लाकमना म प्रतिनिधित्व को राज्य विधान-समार्ज क समान करन के लिए अनुच्छेद 81 (1) (व) म सदोषन किया,गया। छठवें सर्धाः धन (1956) द्वारा बिकी-कर से उत्पत्न विधिक विवादो एव व्यावहारिक कठिनाइया को दूर करने हेतु सप-पूनी म नये विपय-92 (अ) अत प्रातीय विश्वय एव कथ-को जोडा गया। ग्यारहवें सशीधक द्वारा राष्ट्रपति की निर्वाचन पढ़ित में सशीधन की व्यवस्था के याये है। मबीन व्यवस्था के द्वारा उपराद्ध्रपति का सदन के दोना सदनो की समुक्त ठठक मे चुना जाना आवश्यक नही रह गया है। 15वे सशीधन द्वारा याय-पालिका सम्ब थे सशीधन किये गये है एव उच्च यायालय के यायाधीशो के व्यवकाश की उम्र बदाकर 60 से 62 वप कर दी गयी है। एक उच्च यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में पायाधीशो के इस्तान्तरण की व्यवस्था मो की गयी है। 18वे सशीधन द्वारा यह स्पट्ट कर दिया गया है कि अनुच्छेद तीन के अंतगत उन्दित्वित 'राज्य' शब्द के अव मे सभीय क्षेत्र में शामित है। 19वे सशीधन के द्वारा या एक सम्बन्धित के प्रवाद के स्वाप्त की प्रवाद के स्वप्त सम्बन्ध में सभीय कित में शामित है। 19वे सशीधन के द्वारा निर्वाचन न्यायाधिकरणो (Election Inbunals) को समाप्त करके निर्वाचन स्वायाधिकरणो (Election Inbunals) को समाप्त करके निर्वाचन सम्याधीयाविकाओं की सुनवाई का अधिकार उच्च यायालयों को प्रवान कर दिया गया है। फलस्वरूप अनुच्छेद 324 को सशीधित किया गया है।

20वा सशोधन उत्तर प्रदेश के जिला जजो से सम्बन्धित है। सर्वोच्च "यायालय के द्वारा यह निणय दिया गया था कि उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 233 के आधीन
नहीं की गयी है अत जिला जजों के हस्ता तरण का अधिकार सरकार को न होकर
उच्च "यायालय को है। इस निणय से सभी पूर्व एवं स्तमान नियुक्तिया निरस्त हो
जाती थी और उनके द्वारा दिये गये निणयो पर भी विपरीत प्रमाय पढता था। अत
इन नियुक्तियो, पदांतित्या एव हस्तान्तरणों की वैध बनाने हेतु सविधान म अनुच्छेद
233 (अ) जोडा गया।

26वें सघोधन द्वारा प्रीची पस एवं अन्य राजवशीय विश्वेपाधिकारों का अन्त विया गया है। यह सामाजिक विकास की मांग है। 27वें सदीवन द्वारा मीजारम नामक सपीय क्षेत्र के लिए विधानमण्डल एवं मित-परिषद् की व्यवस्था नी गयी है। 28वें सशीधन वा सम्बन्ध अनुब्द्ध 352 के अन्तगत राष्ट्रपति का देश के किसी मान में सकटकालीन घोषणा के अधिवार से हैं। यह सशाधन विराधी दला की मान आदर करते हुए सरकार ने वापस ले लिया था। 31वें सशाधन द्वारा आई सी एस के अधिवारियों को प्राप्त सुविधाआ एवं धवा की सतों में साधन विद्या आई सी एस के अधिवारियों को प्राप्त सुविधाआ एवं धवा की सतों में साधन विद्या गया। 30व सशोधन (अगस्त 1972) द्वारा सर्वोच्च यावालव ने संवाधिकार म संशोधन किया गया है। सशोधित व्यवस्था ने जनुसार व्यवस्थि सम्बन्धी महत्वपूण मामला की अपीत सर्वोच्च व्यायालय में की या सर्वारी है। अभी तर अपीत के लिए विशेष अभूमित प्राप्त करना जावस्थक था या 20 हुआर रुपय या उमते अधिक नी सम्बन्धित विवाद पर ही अपीत नी सुविधा प्राप्त थों।

ा... निम्नितिधित संगोपन ऐतिहासिर परिस्थितिया के परिणाम हैं 1956 ई. र 7वें ससोधन द्वारा नापायी आधार पर राज्यों वा पुन वर्गीटत रिया गया है। 8वें सरोधन द्वारा परिराणित जातिया एवं बनजानिया के लिए विधानमध्यता में 26 बनवरी

1950 ई के पश्चात 10 वर्षों की बजाय 20 वर्षों के लिए स्थान सुरक्षित कर दिये हैं 1^{9द्री} संघोधन 10 सितम्बर, 1958 ई एव 23 सितम्बर, 1958 ई के भारत-पाक सीपाल विवादो सम्बाबी समभौते वे त्रिया वयन से सम्बाधित है। 10वें तथा 12वें संबोधन पुतगाली साम्राज्यवाद के विनाश के परिणाम थे। दादर तथा नगरहवेली 10वे सशोधन के द्वारा भारतीय सच म केन्द्र प्रशासित प्रदेश के रूप म शामिल किये गय हैं। 12वें स्था धन द्वारा दमन एव दीव की पुत्रगाली वस्तियो पर अधिकार करके उन्ह भारत में केंद्र प्रशासित प्रदेश के रूप में बामिल कर लिया गया है। 13वें संशोधन का सम्बन्ध नागालिय्ड राज्य के ज म से है। 14वें सद्याधन द्वारा फेंच औपनिविधाक क्षेत्री-पाण्डुचेरी, कारीकल, माही एवं यनम-को के द्र प्रदासित क्षेत्र के रूप म मारत में मिला लिया गया। 21 वे सशोबन के द्वारा सिधी को राष्ट्रीय मापा की सूची मे स्थान दिया गया। 22वे सशोधन (1969 ई) क द्वारा संसद की विधि बनाकर असम राज्य के अन्तगत जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वशासित राज्य के निर्माण का अधिकार दिया गया। यह सन्नोधन सामाजिक शक्तियो का परिणाम या। 23वें संशोध र द्वारा परिगणित एवं अनुस्चित जातियों के लिए सन 1970 के पश्चात आगामी 10 वर्षों के लिए व्यवस्थापिकाओं में स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था को कायम रखा गया है।

उपरोक्त विश्लेषण के निम्न निष्कप हैं

(1) भीलिक अधिकार सम्बाधी सञ्चोधन सर्वोच्च यायालय के निणया के परिणाम हैं। गोलकनाय विवाद के पूत्र यायालय द्वारा दिये गये निणयों के फलस्वरूप सम्बाद के अधिवार म केवल आधिक संशोधन ही हुए ये पर्राष्ट्र इस निणय ने नीति निर्देशक तस्वो धनाम भीलिक अधिकारों के प्रकृत पर मीलिक अधिकारों म सद्योधन का अधिवार ससद से छोन लिया था। फलस्वरूप संविधान सस्वोधन अधिवार हो गया था।

(2) ज्यानहारिक कठिनाइयो को दूर करने के उद्देश से 11 सशोधन पारित

किये गये हैं।

(3) एतिहासिक एव सामाजिक परिस्थितियों के कारण सविधान में 11

सशोधन हुए हैं।

11/4

इनमें से व्यावहारिक कठिनाइयों के निवारण एवं ऐतिहासिक व सामाजिक परिस्थितियां के कारण हुए संबोधनों का होना स्वाभाविक है। इन्हें मुख्यान में सभी धन नहीं माना जाना चाहिए। यदि सिवधान में वस्तारपुवक अनेक प्रशासकीय एवं सासन की सामाग्य बातों को स्थान ने दिया गया होता तो इनय में अनेक संबोधना की आपदयनता हो न पडती। मिवधान में केवल आठ संधोधन हुए हैं जिनका मीतिर्व अधिकारों से सम्ब घ है। यत भारतीय मिवधान में अधिक मंद्राधनों का आरोप संव नहीं है।

विदेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के सविधाना की तुलना

्रिटन का सविधान अलिखित विकसित एव नमनीय है जबकि समेरिकी सर्वि

धान लिखित निर्मित एवं कठोर है। इसमें संशोधन की स्पष्ट प्रणाली है। जिटेन में प्कात्मक आसन प्रणाली है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिना संचीय राज्य है। अमेरिकी प्रवातम् वाचन अवातः र जनाम प्रवास प्रवास की कहानी है। ग्रेट निटेन के सविधान सविधान | 77 विष्णात विष्णात विष्णात विष्णात विकास एवं सम्मादन में अभिसमया ने महत्वपूर्ण क वाजावत होत क कार्य रवक व्याच्या का सिद्धा तत कोई अस्तित है। का विकास हुआ है। अमेरिका म राष्ट्रपति का पहा ह प्रधाप कुछ जामवाम्या का पहा का ापकाव हुन्या है। जागाएका न राष्ट्रपात का निर्वाचन, सीनेट सम्बंधी सीन्य तथा दलीय व्यवस्था का विकास अभिसमया पर ही आधारित है।

त्रिटिश सविधान संसदीय व्यवस्था प्रधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका में शक्ति-र्यक्करण पर आधारित अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। ब्रिटेन में ससद की सम्भुता है और र्रवकरण पर आवारण अञ्चलात्मक व्यवस्था है। अस्त न वसव मा तम्युवा ह आपिक पुनरीक्षण का पूष अमान है। इसके निवरीत, संयुक्त राज्य अमेरिका के सिव थापक उत्तराताण का त्रण अनाव हा श्रक विषयत, चुडा राज्य अनारका का साम म यायिक सर्वोच्चता के विद्यात को मायता दी गयी है और सर्विद्यान के नात म जातक त्रवाच्या का त्रवाचा प्रकार का त्रवाचा व्यवस्था का त्रवाचा व्यवस्था का त्रवाचा व्यवस्था का त्रवाचा व पायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था है। जिटेन के सर्विधान में मौलिक अधिकारा का स्था पावन अर्थां का जनम्म है। जनम्म प्राप्त का प्रकार स्था के अस्त से कि अधिकारों की रक्षा के उरल ब नहां ह पर पु व्याय क बावम का एक अब पह है। क्यायकारा का की तहीं सिव्यान है न कि सविधान अधिकारा का की तहीं। संयुक्त राज्य अमेरिना ात्प है। जानवान हे न क वाववान जावकारा का लात है। वहुक राज्य जनारक के सिव्यान में प्रथम देस संशोधनों के माध्यम से मौतिक अधिकारों की स्पट्ट व्यवस्था की गयी है।

पक्त भेदा के होते हुए भी अमेरिकी सविधान निटिश सविधान से भगावित हैं। अमेरिकी बाग्रेस ब्रिटिश संसद की माति हिसदनारमद है। अमेरिकी काग्रस को ह। जनारका नामक ।माटस काव का नाम ।हसवनात्मन हा जनारका कामक का मी बित्त पर ब्रिटिश संसद की मीति ही प्रण निय नण प्राप्त है। ब्रिटिश उपास्ताद ही अमेरिकी सविधानवाद का आधार है। दोना सविधानों म जनता की प्रमुख या। रा अभारमा पाननामवाक भा जानार है। बाम पाननाम मानार मान अभिनेता के सिद्धात को स्वीकार विद्या गया है। काम्रेस द्वारा विस्मा ब्रिटिस सस fe को माति तीन सक्ता म ही पारित होती है। मोटे तौर पर ब्रिटिश संसद को माति या गाव वात पायम में हा भारत हाता है। माद का मान समा की माति कांग्रेस का प्रतिनिधि सदन जनता हारा निर्वाचित सदन है। प्रतिनिधि सदन का अध्यस

कॉम त समा के अध्यक्ष की मिति ही स्पीकर कहा जाता है। अमेरिना क सम्बाध मा यह कथन पूणक्ष्मण लागू होता है कि ब्रिटिस सेनियान समस्त सविधानो का स्रोत है और बिटिस ससद समस्त ससदा की जननी है।

न्यायिक निर्णयो द्वारा सविधानो मे सशोधन क भी-क भी देश की यायपालिका द्वारा एस निषय दिय जाते हैं जो संविधान के त्वरूप म मीलिक परिवतन कर देते हैं। स्मरणीय है कि सवयानिक संगोधन-क च्याप्त व वास्त्रिक वार्यक्षा कर्ष व्याप्त का विरास सामा यत उन देशा म अली प्रकार सम्भव होता है जहाँ सवधानिक वासन की व्यवस्मा मुस्यापित एवं नीपनाव न प्रमावयूण का ते संत्रिय एव कियागील हो। के सी ह्वियरे का मत है कि

IJ.

78 | आधुनिक शासनतन्त्र

किसी देश में सविधान को निविध्वित या नष्ट किया जाता है तो इसने लिए कठोः संशोधन प्रणाली को उत्तरदायी ठहराना कठिन है लेकिन हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अधिकास देशा में संशोधन प्रणाली की सफलता का एकमान कारण अर तत्वों का भी सिक्रय होना है। सविधान के संशोधन में अनेक शक्तिया सिक्रय होती हैं। इनमें अत्यधिक महत्वपूण तत्व यायिक व्याख्या है।

बुद्धेक सविधानों में सविधान की व्यास्था (interpretation) का दायित्व स्थप्ट रूप से यायालय को दिया गया है, जसे—आयर गणराज्य के मविधान की धारा 34 के अनुसार सर्वांच्च यायालय को सविधान की व्यास्था का अधिकार है। कुछ देशों में—असे समुक्त राज्य अमेरिया म—यह अधिकार यायपालिका की यायिक वायित्व एव सविधान की प्रवृत्ति के अधिकार से प्राप्त है। न्यायालया को बिधि की व्यास्था का अधिकार होता है। सविधान सर्वांच्च विधि है अत यायालयों को उसकी व्यास्था करने का अधिकार होता है। सविधान सर्वांच्च विधि है अत यायालयों को उसकी व्यास्था करने का अधिकार होता है। सविधान सर्वांच्च के यायिक द्यास्था के जैपित्य का प्रतिपाद प्रसिद्ध अमेरिकी यायाशीश मायल ने 1803 ई (Marbury v Madason) नामक विवाद ये निणय देते : अशिकार सविधान विशोधी विधि को निण्याली धोधित करने का (

फ्रा सीसी गुणराज्य में भी भाग है। यद्यपि पाँचवें गुणराज्य के द्वारा यायालया की कुछ अधिवार प्रदान क्यि गय है जिनका तृतीय गणराज्य म सबया अभाव या और ये अधिकार ससद द्वारा सीमित नहीं किय जा सकते। पाँचनें गणराज्य म अनुच्छेद 56 63 के अ तगत सविधान की व्यास्या का दायित्व नौ सदस्यों सवधानिक समिति को सींपा गया है जिसम उपराप्टपति, सीनेट एव राप्ट्रीय समा द्वारा नियुक्त तीन-तीन सदस्य होते हैं। इस समिति द्वारा यदि किसी विधि को असव यानिक घोषित कर दिया जाता है तो यह विधि निष्प्रमावी हो जाती है। फास के चतुर्य गणराज्य के अनुच्छेद 91 93 के अन्तगत सबधानिक समिति की व्यवस्था थी परातु सयुक्त राज्य अमेरिका के पायिक पूनरीक्षण की व्यवस्था की तुलना में फेच व्यवस्था निस्स देह हैय थी। यायाबीका के कार्यों के सम्बाध में फ्रासीसियों की इस धारणा को अनेक देशा के न्यायाधीशा ने स्वीकार किया है. जैस-नीदरलैण्ड, वेलजियम, स्वीडन एव डेनमाक। परत् जिन देना म यायिक पुनरीक्षण का अमाय है, उनके सदम म यह सोचना गलत है वि वहाँ सविधान सर्वोच्च नही है। के सी ह्वीयरे का मत है कि कुछ मामली मे सविधान द्वारा विधानमण्डल एव कायपालिका की शक्तिया पर अकुश नहीं लगाया जा सकता । ऐसी स्थिति में याधिक पुनरीक्षण का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । जिन देशो म ऐसे प्रतिवाधी की व्यवस्था की गयी है वहाँ केवल यह धारणा बलवती है कि उन निकायी (bodies) पर ही विश्वास किया जाय जिन पर ऐसे प्रतिबाध लगाये गये हैं। विधायक एव प्रशासक से न्यायाधीश को क्या अधिक विश्वासपात्र माना जाय या पापा-धीशा को ही सवधानिक प्रश्ना का निणय करने के लिए शासन के अप निकायों की अपेक्षा अधिक योग्य क्या माना जाय ? जनता को ही जो सप्रम सत्ता को धारणा करती है, व्यवस्थापिका एव कायपालिका की अपेक्षा सविधान की व्यारणा का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए ? स्विटजरलैण्ड म जनमत सग्रह के माध्यम स जनता को सबै धानिक प्रश्ना के निषय करने की अतिम शक्ति प्राप्त है। है। पर तु स्विटजरलण्ड मे सवधानिक जनमत सग्रह एक वाछित अवराध एव सफल व्यवस्था सिद्ध नहीं हुई है। अत यायिक पारीक्षण की व्यवस्था की स्वीकार करने के सम्बन्ध में विभिन्न पूरोपीय देशा में चर्चा होती रही है यद्यपि उसे सभी देशों ने पूरी तरह से अभी स्वीकार नहीं किया है।

यायिक व्याख्या के व्यावहारिक क्रिया वयन का अध्ययन प्रधान रूप में सयुक्त राज्य अमेरिका, कनाइम, आस्ट्रेलिया, जायर गणराज्य एव भारत के सविधाना की समीक्षा ते ही सम्भव है। सविधान की यायालय हारा यायिक व्याख्या (judical interpretation) से क्या तात्य हैं? स्मरणीय है कि यायालया हारा सविधान म सत्तायन हो किया जा एकता और न वे उसकी साधा को ही बदल सकते हैं। वे केवल सविधान के शब्दों की व्याख्या कर सकते हैं और उसके हारा वे परिवनन भी ता सकते

किसी देरा म सविधान को निलम्बित या नष्ट विद्या जाता है तो दमके लिए कठीर सरोभन प्रणाली को उत्तरदायो ठहराना कठिन है लेकिन हम यह निर्म्चत रूप मण्डे सकते हैं कि अधिवादा देगा म सरोधन प्रणाली नी सफतता ना एकमात्र कारण अब तत्वा गा भी सित्रय होना है। सविधान के सत्तोधन में अनक दाक्तियाँ सित्रय होंगे हैं। इनम अत्यधिक महत्वपूण तत्व यायिक व्याख्या है।

कुछेक सविधाना म सविधान की व्याख्या (interpretation) का दायित्व स्पष्ट रूप से यायालय को दिया गया है, जरो-आयर गणराज्य के सविधान की धारा 34 के अनुसार सर्वोच्च यायालय का सविधान की व्याख्या का अधिकार है। बुछ देशो मे--जैसे सयुक्त राज्य अमेरिका मे--यह अधिकार यायपालिका की न्यापिक दापित्व एव सविधान की प्रकृति के अधिकार से प्राप्त है। न्यायालया की विधि की व्यारया का अधिकार होता है। सविधान सर्वाच्च विधि है अत यायालया को उसकी व्याख्या करने का अधिकार है। यह मत अधिकादात उन देशा म स्वीकृत है जहाँ पर औंग्ल सैयमन विधि का सिद्धात साथ है। सविधान की यायिक व्याप्या के जीचित्य का प्रतिपादन प्रसिद्ध अमेरिको यायाधीस माञ्चल ने 1803 ई म मारवरी बनाम मेडीसन (Marbury v Madison) नामक विवाद में निषय देते हुए किया है। यापालय को सविधान विरोधी विधि को निष्प्रमावी घोषित करने का अधिकार है। यही व्यवस्था यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था कहलाती है। यह व्यवस्था अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत एव अनेक मध्य एव लेटिन अमेरिका के देशों में प्रचलित है। लेकिन समी देशा के न्यायालयो को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। कुछ देशों में सविधान के कुछ अश यायपालिका के क्षेत्राधिकार के पर होत हैं। यथा-आयरलैण्ड तथा भारत के सविधान में 'यायालय को ससद की ऐसी विधियों को अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं है जो सविधान म उहिलाखित सामाजिक नीति के अनुरूप हो। स्विस सविधान के अनुसार सधीय यायालय की केटनी की विधिया को अवैधानिक घोषित करने का अधिकार है पर तू संघीय सविधान की ऱ्याख्या का अधिकार फेडरल असम्बली की ही है। स्विस संघीय यायालय को यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

कुछ देवों के सविधान इस प्रदम पर मीन है कि 'पायालयों को सविधान की व्याच्या करने का अधिकार है अध्या नहीं। इन देवों में यह विद्यास मान्य है कि 'पायालया को ऐसे प्रकान के निजय नहीं करने चाहिए। फ़ास के नृतीय गणराज्य के 'पायापीयों ने इस दायित्व का कभी भी निर्वाह नहीं किया यद्यपि सविधान के आधीन ऐसे अवसरा का अभाव नहीं या जब 'पायालय सविधान की व्याद्या कर सकरें थे। वास्त्विकता तो यह है कि फास के 'पायवादियों की होटि में सवजानिक आधार पर ससदीय विधि का 'पायवादिका' द्वारा परीक्षण उचित नहीं है। वे इसे 'पायापीका का दायित्व नहीं भानते थे। फास के 'पायालया नी सामान्य विधि की द्वार्यका करने का तो अधिकार है पर तु वं सविधान की व्याख्या नहीं कर सकते। यही सिद्धान्त पर्वम

फ्रा सीसी गणराज्य मे भी मात्र है। यद्यपि पाचवे गणराज्य के द्वारा यायालयों को कुछ अधिकार प्रदान किये गये हैं जिनका तृतीय गणराज्य म सबया जमान या और ये अधिकार ससद द्वारा सीमित नही किय जा सकते। पाचचें गणराज्य मे अनुच्छेद 56 63 के अ तगत सविधान की व्याख्या का दायित्व नौ सदस्यी सर्वेवानिक समिति को सौपा गया है जिसमे उपराष्ट्रपति, सीनेट एव राष्ट्रीय समा द्वारा नियुक्त वीन-तीन सदस्य होते हैं। इस समिति द्वारा यदि किसी विधि को असवैधानिक घोषित कर दिया जाता है तो वह विधि निष्प्रमावी हो जाती है। फास के चतुव गणराज्य के अनुच्छेद 91 93 के अन्तगत सबैधानिक समिति की व्यवस्था थी पर त सयुक्त राज्य अमेरिका के याथिक पूनरीक्षण की व्यवस्था की तुलना में फ्रेंच व्यवस्था निस्स देह हेय थी। यायाधीशों के कार्यों के सम्बाध में फ़ासीसियों की इस बारणा को अनेक देशा के यायाधीशा ने स्वीकार किया है, जैसे-नीदरलैण्ड, बेलिजयम, स्वीडन एव डेनमाक । पर तु जिन देशों म यायिक पूनरीक्षण का अमाव है, उनके सदम में यह सीचना गलत है कि वहां सविधान सर्वोच्च नही है। के सी ह्वोपरे का मत है कि कुछ मामला मे सविधान द्वारा विधानमण्डल एव कायपालिका की शक्तिया पर अकुश नही लगाया जा सकता । ऐसी स्थिति मे 'याथिक पूनरीक्षण का प्रश्न ही उत्पत्न नही हाता । जिन देशा म ऐसे प्रतिव धो की व्यवस्था की गयो है वहा केवल यह धारणा बलवती है कि उन निकायो (bodies) पर ही विश्वास किया जाय जिन पर ऐसे प्रतिवाध लगाये गये है। विधायक एव प्रशासक से यायाधीश की क्या अधिक विश्वासपान माना जाय या याया धीशों को ही सबैधानिक प्रश्ना का निणय करने के लिए शासन के अप निकाया की अपेक्षा अधिक योग्य क्या माना जाय ? जनता की ही जो सप्रभु सत्ता को धारणा करती है, व्यवस्थापिका एव कायपालिका की अपेक्षा सविधान की व्यारया का अधिकार क्यो नहीं होना चाहिए ? स्विटजरलब्ड म जनमत सग्रह के माध्यम से जनता की सबै-धानिक प्रदेना के निर्णय करने की अतिम शक्ति प्राप्त है। 81 परस्त स्विटजरलैण्ड मे सबैधानिक जनमत सग्रह एक वाखित अवरोध एव सफल व्यवस्था सिद्ध नहीं हुई है। अत "यायिक पुरशिक्षण की व्यवस्था की स्वीकार करने के सम्बाध म विभिन्न युरोपीय देशों म चर्चा होती रही है यद्यपि उसे सभी देशा के पूरी तरह से अभी स्वीकार नहीं किया है।

्यायिक व्याख्या के व्यावहारिक किया वयन का अध्ययन प्रधान रूप से सयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेविया, आयर गणराज्य एव नारत वे सविधाना की समीक्षा से ही सम्भव है। सविधान की न्यायालय द्वारा 'यायिक' व्याख्या (judicial interpretation) से नया तात्य्य है ? स्मरणीय है कि 'यायालया द्वारा सविधान म सदीधन नहीं किया जा सकता और न वे उसकी भाषा की ही बदल सकते हैं। वे केवल सविधान वे सब्दा की व्याख्या कर सकते हैं और उसके द्वारा ये परियनन भी ला नवते

⁶¹ Wheare, K. C op at, p 104

हैं। 'यावालय अपने निषया के द्वारा निष्ठी सर्वेषानिक सद्य या वाक्याश की विष्तृत व्यारया कर मकत हैं तथा अपने पूव निषयों को महाधित, परिवर्तित या स्पष्ट कर सकत हैं। यही नहीं, अपने पूव निषय का व रह या निरस्त की कर सरते हैं। सिवधान रो भाषा अस्पट्ट हो सकती है और ऐसी स्विति म यायाधीशों के उसरी क्यारया के लिए पर्याप्त अवसर होते हैं। यह भी सम्मव है वि यायाधीशों के निजय निभात ने हां, तकहीन हा एवं परिवनन्दील हो, प्रवित्त सामाय धारणा एवं रीति रिवाज के विषयतेत हो, तथा यावाधीशा द्वारा अपने खेताविकार का अतिव्ययण की किया गया हो। ऐसी अवस्था म यायाधीशा की आसोचना तो होती हो है, याविक व्यारया की प्रणाली को भी निवान पे जाती है। मुख्य बात यह है कि यावाधीश का पुर्य काय सविधान के व्यार्था करना है न कि सबोधा करना। जत सविधान म जो परिवत यायाक्षय हारा होते हैं वे व्याल्या सम्प्र वी वायिल के कालस्वरूप होते हैं वे

यायिक व्यारया के फलस्वरूप आधृतिक सर्विधाना म के द्रीकरण का विकास हजा है। के द्वीय मरकार की शक्तियों में वायिक व्याख्या से पर्याप्त वृद्धि भी हुई है। सयुक्त राज्य अमरिका के सर्वोच्च यायालय ने अमेरिकी काग्रेम को सर्विधान द्वारा प्रदत्त शक्ति के अतिरिक्त अत राज्यीय व्यापार के नियमन का भी अधिकार प्रदान किया है। गिब्धन बनाम ओगडन (1824 ई) नामक विवाद से ही सविधान के नज्या की यायालय द्वारा व्यापक अध प्रदान किया जाता रहा है। सविधान द्वारा विभिन्न राज्यो के मध्य व्यापार के नियमा का अधिकार कांग्रेस को प्रदान किया गया है। मृत्य याया धीश माशल ने इस बाक्याश के प्रत्यक शब्द की व्यापक परिमापा दी है । फलस्वरूप के दीय शामन की शक्तियों से वृद्धि हुई। उपरोक्त निषय के बाद के दशकों म अमेरिकी सर्वोच्च पायालय के समक्ष अनेक ऐसे मामल जाये जिनका सम्ब ध अ त राज्यीय एव राज्या तगत व्यापार के सीमा निर्धारण से था। इन सभी विवादों में दिये गर निणया के फलस्वरूप के दीय शासन की शक्ति में वृद्धि हुई है। यह महत्वपूण है कि 150 वप पव जो शक्तिया आर्थिक मामलो में कांग्रेस की प्रदान की गयी थी वे आज मी सयक्त राज्य अमेरिका की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है यद्यपि गहा की जनसंख्या पहले से तिग्नी हो चुकी है और जा कृषि प्रधान देश के स्थान पर अब प्रमुख औद्योगिक देश वन चुना है। अमेरिकी सविधान को नवीन समाज के अनुरूप बनान का श्रेय वहा सर्वोच्च यायालय को है। सर्वोच्च यायालय ने लिए यह इमीलिए सम्मच हो सका अमेरिका ने सविवान की भाषा की ऐसी व्याख्या मम्भव थी। इसक अतिरिक्त, ेरि राज्यों के मध्य अंत राज्यीय व्यापार चालू था। फलस्वरूप यायालया ने संयुक्त राज्य अमरिका वे एवीवरण का प्रमावित किया। स्मरणीय है कि कनाडा म याथालयों है निणया ने फतस्वरूप केंद्र की अपेक्षा प्रा तो की शक्ति वढी है। आस्ट्रेलिया ग अत राज्यीय व्यापार बहुत अधिक नही था फिर मी ने द्वीय शक्ति म यायिक के फनस्वरूप वृद्धि हुई है। देश के औद्योगिक जीवन पर सयुक्त राज्य अमेरिका

कनाडा की अपक्षा आस्ट्रेलिया के ने द्वीय खासन का अधिक नियातण है। 1942 ई में आस्ट्रेलिया के उच्च यायासय द्वारा इनकम टैन्स अधिनियम को, जिसके द्वारा राज्यों ने ने द्वीय अनुदान के बदले आय-कर सवाने के अपने अधिकार का परित्याग कर दिया या, वैध ठहराया था। के इस निष्य के फलस्वरूप राज्यों की राजनीतिक स्वतात्रता बहुत कुछ मध्ट हो गयी है। युद्ध एव सुरक्षा सम्ब ची विक्त के प्रयोग में धार्यिक निष्यों के फलस्वरूप के द्वीकरण हुआ है। सीना सचीय राज्यो—आस्ट्रेलिया, कनाडा एव समुक्त राज्य अमेरिका—के यायावया ने इस बात पर वस दिया है कि के द्वीय विधानमण्डल की ही युद्ध एय सरक्षा विषयक समस्त धक्तिया प्राप्त होनी चाहिए।

कभी-कभी न्यायिक निणया के फ्लस्वरूप सविधान में औपवारिक सशोधन की आवश्यकता पढ़ती है। समुक्त राज्य अमेरिका का 16वा सशोधन (1913) इसी प्रकार के त्यायिक निणया का परिणाम था। इस सवाधन के द्वारा अमेरिकी कामेर की आय कर लगाने की शक्ति पर जा सीमाएँ थी, उन्हें समाप्त किया गया था। मारत का पहला चीथा, 16वा, 24वाँ तथा 25वा सशोधन व्यायिक निणया के फलस्वरूप आवश्यक हो गये थे।

कायपालिका की शक्ति मं मृद्धि आधुनिक सर्विधानों की एक विशेषता है।

पायिन निगयों के फलस्वरूप कायपालिका की शक्ति में मृद्धि हुई है। आस्ट्रेलिया एवं
कनाड़ा के प्यायालयों ने अपनी ससदा को विधि निर्माण की शक्ति कायपालिका को
प्रदान करने की स्वीकृति दी है। सपुक्त राज्य अमेरिका म इसके विपरीत सर्वोच्च
प्यायालय ने काग्रेस ह्यारा विधि निर्माण की शक्ति किसी अप सस्या को प्रदान करने
का समयन नहीं किया। हा, काग्रेस नियम बनाने (rule making) की शक्ति प्रदान
कर सकती है। सविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों ने विकास म गायिक व्याख्या
की भूमिका महत्वपूण रही है। अनेक अवसरों पर सर्वोच्च प्रायालय ने कायपालिका
के नार्यों एवं विधानमण्डल की विधिया को मौलिक अधिकारों का उतिक्रमण वरने के
कार्यों एवं विधानमण्डल की विधिया को मौलिक अधिकारों का उतिक्रमण वरने के
कार्यों पत्र विधानमण्डल की विधिया को मौलिक अधिकारों का उतिक्रमण वरने के

निकप के रूप में यह विचारणीय है कि सविधान की व्यारपा का वायित्व यायालयों को सीपा जाना चाहिए अथवा नहीं एव इसका क्या विकल्प हो सकता है? प्रथम प्रश्न का यह उत्तर दिया जा सकता है कि यह यायालय एव सविधान पर निभर है। अस्पण्ट भाषा वाले सविधान की व्याख्या कठिन होती है और क्षमताहीन यायालयों को यह दायित्व नहीं सीपा जाना चाहिए। सविधान के सन्द्रम में यायिक निजया की सम्मावना से इकार नहीं किया जा सकता। यायिक व्याख्या का विकल्प स्विटजर लण्ड की माति जनमत सब्रह ही ही सकता है। पर तु प्रत्येक राष्ट्र की जनता म इस प्रकार के दायित्व के निवाह की क्षमता नहीं होती। अत सविधान सुस्पट्ट (well drafted) हो तथा 'यायापीश विधिक एव चारित्रिक दृष्टि स इस दामित्व नं सम्पादन नी योग्यना रखते हो ।

परम्पराएँ एव अभिसमय (USAGES AND CONVENTIONS)

भोपचारिक सर्वधानिक संशोधना (formal amendments) एव 'यायिक व्या स्याका (judicial interpretations) द्वारा होने वाले परिवतन स्वीकृत परिवतन हात हैं तथा इ'हे यायालयो द्वारा लागू किया जाता है। व विधिक दृष्टि स मान्य परि वतन होते हैं। लेकिन परम्पराओं एव अमिसमया द्वारा सविधान म होने वाले परिवतन सविधान के अग न होते हुए भी उसी की माति ब धनकारी होते हैं। कभी-कभी सर्वि धान के शब्दों में विना परिवतन के ही जनकी व्याख्या एवं त्रिया वयन इस प्रकार किया जाता है कि वे अपने मूल अय से विल्कूल भिन्न होते हैं यद्यपि यायालय के लिए मूल पाठ और अथ अपरिवर्तित ही बना रहता है। कभी-कभी सविधान की किसी धारा का व्यवहार म बिल्कुल प्रयोग नहीं होता और दीघकाल तक प्रयोग म न आने के कारण वह अश मृतप्राय हो जाता है। परम्पराएँ एव अभिसमय प्रत्येक सविधान-लिखित अथवा अलिखित-म पाये जाते हैं। परन्तु वे अलिखित सविधानो क विकास म अधिक महत्वपूण भूमिका निमाते है। ग्रेट ब्रिटेन के सविधान म अभिसमयो का विशेष महत्व है। ब्रिटेन के सविधान म अभिसमयों के महत्व का प्रामाणिक एव धास्त्रीय विक्लेपण सवप्रथम डायसी ने 1885 ई मे प्रकाशित अपनी पुस्तक An Introduction to the Law of the Constitution में किया है। डायसी का मत है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सविधान लिखिल है पर तु वहाँ भी अलिखित नियमो का विकास हुआ है जो विधि के समान ही प्रभावकारी हैं। अभिसमय का अथ

'परम्परा' एव 'अनिसमय' शब्दो का समानाथीं शब्दो के रूप म प्रयोग किया जाता है लेकिन दोनो शब्दो के अप म बडा अतर है । अभिनमम (convention) का अप ब ध्वकारों नियम से है जिंदे ध्यवहार अथवा आवरण के नियम के रूप में सिंद्यां में किया वेदन से सम्बिधत अस्तिमां द्वारा व पनकारी (obligatory) माना जाता है । लेकिन परम्पराएँ (usages) हसके विपरीत, सामा य अयहार से अधिक मा म नहीं होती है । स्मरणीय है कि एक परम्परा अभिसमय बन सकती है। यह कहना कठिन है कि सक्वारिक आवरण का कोई नियम व धनकारी है अथवा नहीं । ऐसी स्थित म ज्यादा अच्छा यह है कि सविचान से सम्बिधत नियम को निस्पित रूप से परम्परा ही माने। यह अभिसमय भी हो सकता है।

ग्रेट ब्रिटेन का सविधान अभिसमय प्रधान है तथा वहाँ का राजनतिक जीवन अधिकाशत अभिसमयो पर आधारित है। डायसी के अनुसार अभिसमय सवधानिक

⁶³ Dicey Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 1959,

नैतिकता की आचार सहिता है। 68 दूसरे शब्दों में, अभिसमय उस रीति या उग का निर्देश करते है जिसके अनुसार विभिन्न राज्याधिकारियो द्वारा अपने स्वविवेकीय (discretionary) अधिकारो का प्रयोग किया जाना चाहिए। विधिया मौटे तौर पर ही अधिकारियों की सत्ता का उल्लेख करती है, विस्तार की बाते अधिकारियों के विवेक एव वृद्धि पर छोड दी जाती है। अधिकारी को यदि पूरी तरह विधि के द्वारा जकड दिया जाय तो परिस्थितियों के अनुसार काय करने की उसकी क्षमता नष्ट हा जाती है और उसके हाथ पैर बँध जाते है। यत सामा यत अधिकार देवर विस्तार के मामलों में अधिकारियों को स्वविवेकानुसार काय करने की स्वत तता प्रदान की जाती है। अभिसमय इससे बढकर यह बतात है कि अधिकारी को स्वविवेकीय शक्तियों का उचित उपयोग किस प्रकार करना चाहिए । श्रायसी ने अभिसमय की परिभापा निम्न शब्दा म दी है सविधान के अभिसमय वे 'रीति रिवाज' या 'समभदारी' (under standings) हे जिनके जनसार सप्रभ विधानमण्डल (ससद) के विभिन्न सदस्या को अपने स्विविवेकीय अधिकारा का प्रयोग करना चाहिए, चाहे उ हे सम्राट के परमा-धिकार अथवा ससद के विशेषाविकार ही कहा जाय । के **जॉन स्टअट मिल** ने डायसी द्वारा उल्लिखित अभिसमयो को सविधान के अलिखित सिद्धा त' की सन्ना दी है। 60

ए सन (Anson) इ.ह सविधान के रीति रिवाज कहता है। 67 डॉ॰ आग के अनुसार अभिसमय स तात्पय "समभदारी, प्रचलन एव आदता से है जो सावजनिक अधिकारियों के एक बड़े भाग के वास्तविक सम्ब थी एवं कार्यों की नियमित करते हैं। ' 68 कीथ क अनुसार अभिसमयो का विस्तार सभी सबैधानिक सम्बाधी से है एव वे विधिक अधिनियमा के व्यावहारिक अथ का स्पष्ट करते हैं। हैं अभिसमय अलिखित हैं। फ्रीमन के शब्दों में यह राजनीतिक नतिकता की सम्पण प्रणाली है और सावजनिक जीवन से

⁶⁴ 'Code or rules of 'constitutional morality' "-Dicey op cit,

p 424
The conventions of the constitution are customs or funderstand ings' as to the mode in which the various members of the sovereign legislative body should exercise their discretionary autho rity, whether it be termed the prerogative of the Crown or privileges of the Parliament—Dicey op at, p clu and p 423 Conventions are unwritten maxims of the Constitution—J

⁶⁶ Mill, cited by Jennings The Law and the Constitution, 1954, p 80

⁶⁷ Anson defines conventions as "the customs of the Constitution" -Cited by Sir Ivor Jennings The Law and the Constitution, 1954.

Conventions consist of understandings, practices and habits 68 which although only rules of political morality, alone regulate a large portion of the actual day-to day relations and activities of the public authorities '- Ogg and Zink Modern Foreign Governments, 1956, p 29

⁶⁹ Keith, A B The Constitutional Administration and Lows of the Empire

1 1.

सम्बिचित व्यक्तियों की निर्देश सिहता है जो किसी विधि अथवा सामा य विधि का अर्प तो नहीं है कि तु व्यवहार में अर्याधिक पवित्र सानी जाती है। ब्रिटिश सिवधान के लिखित अदा के साथ अलिखित अदा का विकास हुआ है जिसे हम अलिखित या अपि समयात्मक सिवधान की सता दे सकते हैं। 10 बार जे जितस्य के अनुसार अभिसमय विधिक सिवधान को सता दे सकते हैं। 10 बार जे जे जनुस्य तनाति हैं। सिवधान को सत्या जीत, विकसित एव परिवर्तित विचारों के अनुस्य तनाति हैं। सिवधान राष्ट्रीय सहियान स्वय काय नहीं करता, उस मनुष्य सचालित करते हैं। सिवधान परिवर्धित एव सिवधान स्वयं का य नहीं और सहयोग की मावना य न की माति ही आवस्यक है। सब धानिक अभिसमय इस सहयोग को सम्भव वनाने के नियम हैं। "सिवधान का राष्ट्रीय जीवन की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार बदलना आवश्यक होता है। अत पुरागी विधियों को नवीन व्यवस्था एव उसकी आवस्यक्ताओं की पूर्ति के अनुस्य रहना आव स्थक है। सब वानिक अभिसमय ऐसे नियम हैं जो व्यक्तियों द्वारा इसी उद्देश्य के लिए विक्तिसत किये जाते हैं। "वे ह्वीयरे के अनुसार अभिसमय सिवधान क गर विधिक नियम हैं। "व

लेकिन अमिसमय उल्लिखित विधि नहीं है। विधि एव अभिसमयो मे तारिक भेद है। विधि विधानमण्डल द्वारा पारित की जाती है। अमिसमयो को पारित नहीं किया जाता अधितु अयहार के फलस्वरूप उनका विकास होता है। यह सम्मय है कि आज का अभिसमय कल विधि का रूप चारण कर ते। विधि वे उल्ल्यम पर दण्ड दिया जाता है, अमिसमयो के उल्ल्यम पर दण्ड देना सम्मय नहीं है और न ग्याम स्व विधि भे मौति अभिसमयो के उल्ल्यम पर दण्ड देना सम्मय नहीं है और न ग्याम स्व विधि भे मौति अभिसमयो का पालन ही करा सकत हैं। किसी अमिसमय का मा होने पर मुक्दमा नहीं चलाया जा सकता, जसा कि विधि के मय करने वालों ने विचद्ध होता है। विधि अभिसमया को अपेक्षा अधिक माय होता है। अमिसमया का पालन विधि की मौति निष्यत करव्य नहीं माना जाता। विधि स्थायी (static) है, अमिसमय

^{70 &#}x27;We now have a whole system of political morality a whole code of precepts for the guidance of public men which will not be found in any page of either the statute or the common law, but which are in practice held hardly less sacred than any principle. In short by the side of our written law there has grown up an unwritten or conventional constitution '—Freeman, cited by Diecy op cit, p. 418

⁷¹ Constitution make the legal constitution work they keep II in touch with the growth of ideas The constitution does not work itself, it has to be worked by men. It is an instrument of national cooperation and the spirit of cooperation is as necessary at the instrument. The constitutional conventions are the rule claborated for effecting that cooperation "—Dr. Jennings Th. Law and the Constitution 1954 p. 81

⁷² Conventions are the 'non legal rules in their relation to a continution' —Wheare, K. C. op at, p. 121

निरतर बदलत रहते है। विधि म यदि परिवतन होता है तो वह एकदम होता है। इसक विपरीत, अमिसमया का श्रमिक विकास होता है। नये अभिसमय समय पर उत्पन्न हात रहत हैं और पुराने समाप्त होते रहते है। उदाहरण के लिए, डिज-रायदी द्वारा इस अभिसमय की स्थापना हुई थी नि निर्वाचना म मित्र परिवद् ने पराजित होन पर उसे तुरत त्यापपन से देना चाहिए। ससदीय अधिनयम (1911 ई) के द्वारा इस अमिसमय को विधिक आधार प्रदान विया गया। नवीन अभिसमय के विश्विक होना का एक अय उदाहरण है कि 1923 ई म बाल्डविन को लाइसमा म अनुदार दल के नेता कजन के स्थान पर पचम जॉज ने इस आधार पर प्रधानमानी चुना या कि वह अनुदार दल का कॉम स समा (जो जनता का निर्वाचित सदन है) के नता का प्रधानमानी नियुक्त करना अपेक्षाकृत लोक तन्नीय मावना के अधिक अनुकूत है।

द्विटन के क्यानिक अमिसमयों का कई वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, यथा— राजा, मिनमण्डल, ससद एव राष्ट्रमण्डल सं सम्बन्धित अभिसमय। ब्रिटेन के कुछ महत्वपूण अभिसमय निम्नवत् है

- (1) राजा मिनया के परामश से काय करता है।
- (2) राजा द्वारा कॉम स सभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमानी नियुक्त किया जाता ह एव मनिया की नियुक्त प्रधानमानी की सलाह से की जाती है। राजा को प्रधानमानी के द्वारा प्रस्तावित मनियण्डल के सदस्यों के नामां में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।
 - (3) राजा मित्रमण्डल की बैठका में माग नहीं लेता।
 - (4) प्रधानम"नी के परामश पर राजा ससद को भग करता है।
- (5) सम्पूण मन्तिमण्डलीय ब्यवस्था अभिसमयो पर आधारित है। मित्रमण्डल कॉम स समा के विश्वासपय त ही पदारू रहता है। यित्रमण्डल के विश्व अविश्वास का प्रस्ताव पारित हाने पर या मित्रमण्डल द्वारा प्रस्तावित विशेषक के विश्व मत आगे पर मित्रमण्डल को त्यागपन देना पडता है। ऐसी स्थिति म प्रधानमानी ससद को मग करके नक्षीन निर्वाचनों को माण कर सकता है जो अनिवायत राजा द्वारा स्वीकार की जाती है। यदि नवीन निर्वाचनों में मित्रमण्डल हार जाता है तो वह नवीन काम स समा के अधिवेशन के पूब ही पदस्याम कर देता है। ऐसी स्थिति मे प्रधानमानी पून काम स समा के अधिवेशन के पूब ही पदस्याम कर देता है। ऐसी स्थिति मे प्रधानमानी पून काम स समा के जिधवेशन की माग नहीं कर सकता।
- (6) मानी कामास सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते है। नीति सम्बाधी किसी प्रश्न पर यदि कोई एक मानी पराजित हाता है तो पूरे मिनमण्डल को त्यागपन देना पडता है। लेकिन व्यक्तिगत आचरण अथवा दुराचार के लिए केवल सम्ब-धित मानी ही उत्तरदायी होता है।
 - (7) कॉम स सभा का अध्यक्ष जर्यात् स्वीकर दलीय आधार पर चुना जाता

है पर तु अपने निर्वाचन के परचात वह दक्षीय सदस्यता का परित्याग कर देता है और निदलीय एवं निष्पक्ष रूप से आचरण करता है।

(8) लॉड समा सर्वोच्च पुनरावेदनीय यायालय है पर तु अमिसमय के अनु

सार केवल 9 विधि लॉड ही पुनराविदनीय यायालय के अधिवेदान म भाग लेते हैं। (9) अभिसमय के अनुसार राजा निषेपाधिकार का प्रयोग नहीं करता।

(9) अभिसमय के अनुसार राजा निषयाधिकार का प्रयोग नहीं करेता। (10) विधि बनने के पूब प्रत्येक विवेयक का तीन दाचनों में पारित होना

(10) विविध्यक्त के पूर्व प्रत्यक विध्यक्त की तीन विधिन। से नार्र्स ट आवश्यक है।

(11) ससद का वप म कम से कम एक अधिवेशन अनिवासत होना चाहिए। (12) 1923 ई के पूज प्रधानम नी कॉम स समा या लाइसमा दोना म से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता था। 19वी सदी में अनेक प्रधानम श्री—यथा, पामस्टन, सेलिसवरी आदि—कॉडसमा के सदस्य थे। परतु 1923 ई म राज जाज पचम ने नवीन अभिसमय की स्थापना की और उन्होंने कॉम स समा के अनुदारस्तीय बहुसत दल के नेता को यानम श्री चुना। तब से कॉम स समा न सनुदारस्तीय

ही प्रधानम त्री होता है। (13) ससदीय विधि द्वारा संघियों की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

(13) ससदाय विषय हारा साधवां का स्वाकृत आवस्यक नहा ह। (14) यदि लॉडसमा कॉम स समा द्वारा पारित किसी विवेयक का विरोध करने पर इड है तो राजा का यह कतव्य है कि लाबसमा के विरोध को निष्प्रमावी करने के लिए जितनी सन्या में पीयस (लॉडसमा के सदस्य) नियुक्त करने का प्रधान-मनी परामदा दे नियुक्त करे।

(15) राष्ट्रमण्डलीय विषयो म राजा राष्ट्रमण्डल विभाग के मात्री के परामश से ही काम करता है।

स हा काम करता है।

(16) औपनिवेशिक व्यवस्था स्वयं अभिसमय पर आधारित है यद्यपि अनेक सम्बंधित अभितमय 1931 ई के वेस्टिमिनिस्टर अधिनियम के रूप में विधि का रूप भारत कर चुके हैं। परतु अभी भी कुछ अभिसमय हैं—जसे, शाही उत्तराधिकार—

जिनके सम्बन्ध मे उपनिवेशो नी ससदो की स्वीकृति आवश्यक है।
(17) साबजनिक अधिनियम का निर्माण करत समय शासन को सम्बन्धित

(17) सावजनिक अधिनियम का निर्माण करत समय शासन को सम्बिधि हितो से परामश करना चाहिए । समुक्त राज्य अमेरिका म भी बुख अभिसमयो का विकास हुआ है । यथा—

(1) राष्ट्रपति का निर्वाचन दो वार स अधिक नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति वार्षिगटन ने तीसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने से इकार कर दिया था। तभी से यह परम्परा पढ़ी है। परानु राष्ट्रपति रूजवेल्ट इस परम्परा का उल्लंबन नरके चींथी बार राष्ट्रपति चुने मय थे। फ्लस्वरूप 1953 ई म राष्ट्रपति का कायकाल सम्बाधी अधि नियम कींग्रेस द्वारा पारित किया गया एव दो बार भी जबिंच राष्ट्रपति के लिए अधिर

तम अवधि निर्धारित को गयी है। (2) राष्ट्रपति सविधान के अनुसार निवाचक मण्डल द्वारा चुनाजाना चाहिए। परन्तु व्यवहार मं वडा अत्तर है। राष्ट्रपति पर के लिए विभिन्न दला द्वारा उम्मीद-वार पहले से ही निक्ष्यित कर लिये जाते हैं तथा निर्वाचक मण्डल के सदस्य अपने दलीय उम्मीदवार का दी मत देत है।

(3) प्रतिनिधि समा की सदस्यता के लिए केवल उसी निर्वाचन क्षेत्र से

उम्मीदवार खडा हो सकता है जिसकी सूची म उसका नाम है।

(4) अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर निदलीय एव निप्पक्ष नही होता।

वह प्रमुख दलीय नेता होता है।

(5) उच्च पदो की नियुक्तियों के सम्बाध में राष्ट्रपति सम्बाधित सीनेटर से पहले ही परामस कर लेता है। इसे सीनेट सम्बाधी सीजाय कहते हैं। इसकी उपेक्षा को सीनेट के सदस्य वर्दास्त नहीं करते।

(6) कांग्रेस के दोना सदना की काय-विधि प्रयाओ एव परम्पराओ परआधा-

रित है। सविधान इस सम्बन्ध में मौन है।

अमेरिकी राजनैतिक जीवन की परम्पराएँ एव रीति रिवाज सविधान के शीप पर स्थित एक पिरामिड की मौति है। इनका आधार दीवकालीन प्रचलन है। अमेरिकी राजनतिक व्यवस्था मे सशोधना एव अभिसमयो ने इतना योगदान नहीं दिया है जितना कि प्रयाजा एव रीति-रिवाणा ने प्रदान किया है और जिसके कारण राजनतिक दल शासन यात्र का सचालन कर रहे है। 73 प्रो० मुनरो ने के इस कयन का पूण समयन किया है। उनका कथन है कि अमेरिकी सविधान भी रीति रिवाजी एवं परम्पराओ पर बहुत कुछ निभर है। सम्मवत मूख्य परम्पराएँ राजनैतिक दला के प्रभाव एव महत्व से सम्बाधित है जिनका सधीय सविधान म कही उल्लेख नहीं है परातु आज वे सविधान के त्रिया वयन के लिए के द्वीय महत्व की है। भारत का नवीन सविधान लिखित है पर तु यहा भी कुछ अभिसमयो की स्थापना हुई है, जसे राष्ट्रपति नाम-मान का अध्यक्ष है। यद्यपि राष्ट्रपति को समस्त कायपालिका शक्ति सर्विधान द्वारा प्रवान की गयी है परातु उसका प्रयोग मिनमण्डल ही करता है। निपेधानिकार का प्रयोग मित्रमण्डल के परामर्शानसार ही किया जाता है। के द्र एवं राज्यों के मध्य अनेक सम्मेलनो की व्यवस्था का विकास हुआ है, जसे-मृत्यमानी सम्मेलन, गवनरा का सम्मेलन, आदि। स्पीकर की स्थिति ब्रिटेन व अमेरिका के स्पीकरा के मध्य की है। प्रधानमात्री द्वारा ससद के विघटन की माग को राष्ट्रपति अस्वीकार नहीं कर सक्ता ।

अभिसमयो के वालत का आधार

अभिसमय विधि नहीं हैं और उनके उल्लंघन के लिए दण्ड नहीं दिया जा सकता, तो प्रस्त यह है कि उनका पालन क्या होता है ? क्या अभिसमय प्रमावहीन नहीं हैं ? उनके पीछे कौन सी छक्ति है ?

 ⁷³ See Beard, C A American Government and Politics, 1955, p 23
 74 Munro, W II The Government of the United States, p 69

डायसी ⁶ ने इस सम्बाध में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि अभिसमर्थों का पालन महाभियोग के भय एव जनमत के कारण किया जाता है तथा महत्वपूण अभिसमयो के पीछे विधि की शक्ति निहित है। अभिसमया का उल्लंधन करन वाला किमी न किसी विधि के उल्लंधन का दोपी होता है। ऐसी स्थिति म वह पायालय द्वारा दण्डनीय हागा । मान लीजिए, काम स समा म पराजित कोई प्रधानम त्री पर त्याग नहीं करता तथा सम्राट के सहयोग स पदारूढ बना रहता है। दुछ महीने ती वह ऐसा कर सकेगा। उसके इस असर्वधानिक काय को भले ही किसी यायालय म चुनौती न दी जा सके पर तुनये वय के प्रारम्भ म उसे आगामी वय के शासकीय व्यय के लिए ससद से धन की स्वीकृति अवस्य लेनी पडेगी । यदि प्रधानमात्री विना ससद की स्वीकृति के धन व्यय करता है जथवा कर लगाता है तो उसके ये काय विधि के विरुद्ध होगे और वह अपराधी होगा तथा उचित दण्ड का मागी होगा। अमातुष्ट ससद से वह सहयोग प्राप्त नहीं कर सकेगा। अत अभिसमया का उल्लंबन अत में विधि के उल्लंघन म परिणत हो जायेगा। लेकिन डायसी का यह तक पूणत सत्य नहीं है और केवल थोड़े से अभिसमयों से ही सम्बधित है। सभी अभिसमया के सम्ब ध मे यह सत्य नहीं है। जनेक अभिसमय ऐसे है जिनका उल्लंघन होने से कोई कानुन मग नही होता । अत उनके सम्ब व मे दण्ड का कोई प्रश्न उत्पन ही नही होता । उदाहरण के लिए, 1862 ई मे प्रधानम त्री ब्लेडस्टोन ने प्रत्येक कर प्रस्ताव को ससद द्वारा पृथक पृथक रूप से स्वीकृत कराने के स्थान पर एक ही अय विधेयक म एकतित करके पारित करा लिया था। इससे किसी विधि का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। इसी प्रकार, प्रधानम नी लायड जाज न प्रथम युद्ध-काल म युद्ध मित्रमण्डल की स्थापना की थी। इससे किसी स्थापित विधि का उल्लंघन नहीं हुना । इसी प्रकार, किसी विधि नो यदि ससद तीन बाचनों के स्थान पर दो बाचनों में ही पारित कर देती है तो किसी भी विधि का उल्लंघन नहीं होता। किसी अभिसमय के उल्लंघन के कारण किसी विधि से तत्क्षण सघप की भी सम्मावना नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, यदि मृत्रि मण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव बजट अथवा आर्मी एक्ट के पश्चात पारित किया जाता है तो मित्रमण्डल आगामी वजट के पारित होने के समय तक पदाहर रह सकता है। 1931 ई म प्रधानम नी रेमजे मक्डोनस्ड ने संयुक्त उत्तरवायित सम्ब थी अभिसमय की उपक्षा की थी पर तु उसे किसी भी विधिक अपराध का दापी नहीं ठहराया गया था। लावेल ने इसी सुदस में कहा है कि ब्रिटिश ससद प्रति वर्ष वित्त एवं सेना अधिनियम पारित करन के लिए वाघ्य नहीं है। वह स्थायी सन अधिनियम पारित कर सकती है एव वतमान करा का कुछ समय के लिए स्थायी बनी सनती है तथा शासन क सामा य व्यथा को स्थायी व्यय-भार घोषित कर सकती है।

⁷⁵ Dicey of cit, Ch XV pp 439 473
76 Lowell, A L Government of England, Vol I, (1908), p 114, cited by Ogg and Zink of cit, p 31

डायसी के इस तक की भी आलोचना की जाती है कि महामियोग के कारण अभिसमयो का पालन होता है। ग्रेट ब्रिटेन में महाभियोग का नियम दीघकाल तक प्रयोग न किये जाने के कारण मृतप्राय हो चका है। उसकी पूनर्जीवित नही किया जा सकता । डायसी ने स्वय इसे अपर्याप्त कारण माना था।

डॉo ऑग⁷⁷ का मत है कि अभिममयों के पीछे लोकमत की वास्तविक शक्ति है। अभिसमय का पालन जनमत या लोकमत के कारण किया जाता है। लोकमत चाहता है कि उनका पालन किया जाय एव उनके उल्लंघन को स्वीकार नहीं किया जायेगा। पराजित मीजमण्डल को पदत्याग करना ही चाहिए क्योंकि (ब्रिटिश) लोकमत ऐसे मिनमण्डल का पदारूढ रहना स्वीकार नहीं करेगा। इसी प्रकार, ससद का प्रति वय वापिक अधिवेशन आहत किया जाना अनिवाये है जिससे कि राज्य के विभिन विषयों पर दिचार किया जा सके। इसी प्रकार, जनता यह वर्दाश्त नहीं करेगी कि लाड-समा के सभी सदस्य लॉडसभा की यायिक वठको मे माग ले। यही अ य अभि-समयों के बारे में भी सत्य है। जनता की यह इच्छा है कि उसके प्रतिनिधियों द्वारा स्वीकृत विधि के विरुद्ध राजा निर्पेषाधिकार का प्रयोग न करे। स्पष्ट है कि अभि समयो के पीछे लोकमत की शक्ति है। परन्तु डामसी इसका उचित नहीं मानते थे। उनका कथन है कि लाकमत के अनुरूप कार्य करना स्वय एक अभिसमय मान है और किसी अभिसमय को शेप अभिसमयो का आधार मानना युक्तिसगत नहीं है। 18

डॉo जेरिंग्स ° क जनुसार अभिसमयो ना पालन सामाय स्वीकृति के कारण होता है, न कि शक्ति के कारण। यदि जनता उनका पालन नहीं करना चाहती तो उनका पालन शक्ति से नहीं कराया जा सकता । लाबेल का कथन है कि अभिसमयो का पालन इसलिए होता है क्यांकि वे आदरसूचक नियम होते है और उन्ह लाकमत का परम्परा से समयन प्राप्त होता है। 80 अग्रेज स्वसाव से ही रूढिवादी है अत उह अपने अभिसमयो से प्रेम है। चिक जनता अभिसमयो का आदर करती है अत जनके प्रतिनिधियों की सरकार भी उनका पालन करती है। लावेल का उक्त मत टापसी के मत स अधिक प्राह्म है। परत लोकमत के समयन का आधार केवल रूढि नहीं है। व्यक्तिया द्वारा किसी पुरातन बात या नियम का समर्थन केवल इसलिए नही किया जाता कि वह प्राचीन काल से वली आ रही है अपित इसलिए किया जाता है कि सम्बर्धित नियम या व्यवस्था प्राचीन काल की मांति ही उपयोगी होती हैं। साबेल न उपयोगिता के तत्व का मायता नहीं दी है अस उसका मत पुणत स्वीकाय नहीं है। पीइस के अनुसार अभिसमया के पीछे राजनीतिक स्वीकृति है। B1

81

Ogg and Zink op cit, p 31 77 78

Dicey of cit, pp 444 445 Jennings The Law and the Constitution, (1954), p 98 79 80

[&]quot;The conventions are observed because they are meded of honour'—Lowell, A L, cited by Ogg and Zink op cit, p 31 Greaves The British Constitution, (1956), pp 16 and 18

एक मत यह भी है कि अभिसमया के पीछे निह्त शक्ति उपपाणिता है। इससे सविधान को परिवर्तित परिस्थितियों भ मुनार रूप से बलाने म मुविया हाती है। उपयोगिता की हृष्टि से कुछ पुरानी प्रथाए लुप्त हो जाती हैं और कुछ नवीन प्रयाज का उदय होता है।

सास्की के अनुसार अभिसमयों के आदर के दो कारण है—प्रथम, अर्थि समय प्रवित्त सामाजिक सर्वधानिक सिद्धान्ता के अनुरूपहोन के साथ साथ उनके त्रिया ज्यान में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए, यिनमण्डल की वठकों की अध्यक्ष होते प्रधानमनी करता है। यह असिसमय है। पहले राजा मिनमण्डल का अध्यक्ष होते था। वित्तय कारणों से राजा का स्थान प्रधानमनी ने ले लिया। जाज हतीय के पुन इस अधिकार को पाने की चेटा की थी पर खु उसे तीज विरोध का सामग करना पड़ा। स्वष्ट है कि प्रधानमन्त्री के द्वारा मिनमण्डल की अध्यक्षता की रीति स्वीकृत एव विकसित लोकतानारसक प्रवृत्ति के अधिक अनुकूल होने के कारण स्थाम हो गयी। इसका अथ यह हुआ कि जिटिया अभिसमय सोकतान की आवर्यकताओं ह अधिक अनुकूल हो स्वस्त से स्वित स्वीकृत है। स्वस्त से स्वा स्वस्त है। स्वस्त से स्व

लास्की नो हिन्ट म अभिसमय की मायता का दितीय कारण यह है कि प्रेट ब्रिटेन के सभी राजनीतिक दल देख के राजनैतिक एव सामाजिक ढाँचे की आधारभूत बातों के सम्बाध में एकमत हैं। फलस्वरूप उनसे सम्बाधित समान अभिसमय भी उह समान रूप से मान्य हैं।

अमिसमयो की मायता विषयक उपरोक्त समीक्षा से यह स्पष्ट है कि उनकी मायता का आधार लाकमत का समयन एवं उनकी उपयोगिता है। सास्की का मत

भी वडा सबल है।

समीक्षा—अभिसमयों का सबैधानिक महत्व है। बायसी का कथन है कि अभि
समय द्वारा नाउन की स्वविवेकीय शिक्यों के प्रयोग का निर्धारण किया जाता है।
इसके अतिरिक्त, ससद एवं मिन्सण्डल को जनता की इच्छा के जनुसार काम करन के
लिए बाच्य किया जा सकता है। "सं सवधानिक गतिकता की आवार-सिहता है (और
वे) जनप्रभुत्व की उपलब्धि कराते हैं।" विशिष्ठ हारा ससद पर कोई प्रतिव ध लगाली
सम्भव नहीं है। इसके लिए दूसरे प्रकार का प्रतिव थ आवस्यक है। अभिसमय सहर्ष
द्वारा निर्मित नहीं है और उह लाउना भी उसके लिए सरत नहीं है। अभिसमया की
जम्म जनता की ओपित्य-युद्धि संहुआ है अत ससद उनके उल्लंधन का साहस नर्श
कर सकती।

का० जैनिम्स न अनुमार अभिसमय दा महत्वपृथ नत्तव्य सम्पादित करते हैं। प्रथम, परिवर्गित सामाजित आवश्यकताओ एव राजनीतिक विचारा कं अनुकूत साम्न

⁸² Laski H J Parliamentary Government in England, Ch I, 1047 pp 52 70

यवस्था को ढालने म सहायता प्रदान करत है। द्वितीय, शासको को शासनयन्त्र के उचालन में सहयाग प्रदान करते हैं। मिनमण्डलीय शासन प्रणाली के काय में अमि-तमय सहयोग को सम्भव बनाते है । इसके अतिरिक्त, ग्रेंट जिटेन एव उसके उपनिवेशा हा सहयोगपूरक काय करने में ये सहायता करते है । <mark>जेनिग्स</mark> के अनुसार *'*वे विधि की पुरुत हडिडया को मास से ढकने का काय करते हैं^{7 83} तथा विधिक सविधान को किया-. तील एव समाज के विकसित विचारों के अनुरूप बनाते हैं। उनके द्वारा मिनमण्डल एव कॉम स सभा में सहयोग स्थापित होता है तथा राजनतिक सप्रज़ के प्रति कानुनी सप्रभ् ससद) को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अभिसमयो के द्वारा ही निरक्श राज-त त्रीय व्यवस्था का लोकत त्रीयकरण सम्मव हो सका है। उह अलिखित नियमो की सज्ञा देना ठीक नहीं है। जनेक अभिसमय लिखित रूप में पाये जाते है। उदाहरण के लिए. विधानमण्डल के दोनो सदना से सम्बन्धित स्थायी नियम (standing rules) लिखित होते हैं। कुछ देशों में ये नियम विधानमण्डल द्वारा पारित किये जाते हैं एव देश की विधि का जग होते है। स्वीडन एव फिनलण्ड म ये निग्रम सर्वोच्च सावपवी या आवारभत विधि (organic law) के नियम है जो सविधान का अग नहीं कहे जाते है। लेकिन अनेक देशों में इन नियमों को स्थायी प्रस्तावों के रूप में विधानमण्डली द्वारा पारित किया जाता है, अत ये विधि का जग होते है । अपनी काय पद्धति को नियमित करने के लिए प्रस्ताव के रूप में इन नियमों को भले ही विधानमण्डल द्वारा पारित किया गया हो, लेकिन अनेक विचारक उन्हें विधि की सज्ञा न देकर अधिक से अधिक लिखित अभिसमय मानते हैं।

ह्वीपरें के अनुसार अभिसमय सविधान की निम्न प्रकार से प्रमावित करते है (1) अमिसमया के कारण सविधान की कुछ धारा या धाराएँ निरथक हो जाती हैं। उसने यहदों म "अमिसमय विधि की मुखाआ को निष्क्रिय नगा देते हैं।" रमरणीय हैं कि वे उह संशोधित या समाप्त नहीं करते अपितु विधि का उपयोग असम्मव बना देते हैं। उसहरण के लिए, विभिन्न राज्याध्यक्षों की विधानमण्डल हारा पारित विधि को अस्वाकार करने या निवेधाधिकार की शक्ति अभिसमय के फलस्वरूप निरथक बन गयी है। स्थीडन, डेनमाक, नावें एव ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलीय देशों के राज्याध्यक्षों हारा निवेधाधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता है। राष्ट्रमण्डलीय देशों से गवनर जनरतों हारा निवेधाधिकार के प्रयोग सम्बाधी अधिसमय इगलण्ड की परम्परा या रीति-रिवाज पर लाधित है।

अमेरिकी राष्ट्रपति पर तीसरी बार चुने जान पर प्रतिव व लगाया गया है। यह इसका प्रमाण है कि अभिसमय सिवधान द्वारा प्रदत्त आक्ति को निरक्षक वना दते हैं अमेरिकी सिवधान में तीसरी वार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन का कोई प्रति-

¹⁸³ They 'provide the flesh which clothes the dry bones of the law"—Dr Jennings The Law and the Constitution (1954), p 80
184 Wheare, K C Modern Constitutions, (1966), pp 123 133

किस अभिसमय का विकास होता है। अभिसमयो का एक और प्रमाव मी होता है। अभिसमय के कारण सविधान द्वार प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उन व्यक्तियो द्वारा नहीं किया जाता जि हे वह शक्ति प्रदान है जाती है। उसे अय व्यक्तिया व्यक्तिया द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए इगलैण्ड के राजा को विधिक रूप में सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं परन्तु वह उनका प्रयोग प्रधानमंत्री एव मित्रमण्डल की सलाह से ही करता है। भारत के सविधान ह राष्ट्रपति कायपालिका का अध्यक्ष है परातु वह अपनी इस शक्ति का प्रयोग मित्र मण्डल के परामदा से ही करता है। कनाड़ा के सविधान म मननर जनरल की पर मश देने के लिए एक परिषद है जिसके सदस्य उसके ही द्वारा नियुक्त किय जाते हैं एव उसे उनको अपदस्य करन का भी अधिकार होता है। लेकिन व्यवहार म गर अभिसमय वहाँ विकसित हुआ है कि गवनर जनरल प्रधानम त्री के परामश प्रीवी कौसिल को नियुक्त करता है। इसी अभिसमय का निकास थोडे बहत परिवतन से आस्ट्रेलिया, 'यूजीलण्ड, दक्षिण अफीका स्वीडन, नार्वे हॉलण्ड एर वेलजियम म भी हुआ है। अधिकाश ससदीय कायपालिका प्रयान देशा म इस असि समय क फलस्वरूप राज्याध्यक्ष की विधिक शक्ति शासन का सचालन करन वा क्षाय व्यक्तियों को हस्ता तरित हो गयी है। प्रधानमात्री की नियक्ति के सादम मंगी अभिसमय विकसित हुआ है कि उस बहुमत दल का नता होना चाहिए। प्रधार मात्री क परामश पर विधानमण्डल को राज्याध्यक्ष द्वारा विधटित किया जाता है यद्यपि यह उसका विधिक विशेषाधिकार है। यही नहीं कायपालिका शक्ति के प्रयार यद की घोषणा, नियुक्तिया वदशिक सम्बन्धा के संचालन में सविधान द्वारा राज्य ध्यक्षा को प्रदत्त विधिक शक्तिया का प्रयोग अभिसमय क अनुसार अ य व्यक्ति (प्रधानम शी सहित मि प्रमण्डल) द्वारा किया जाना है और व ही इन कायों कि विधानमण्डल व प्रति उत्तरदायी हात है। स्पष्ट है कि अभिनमया के फलावर विधिय गक्ति जाय हाथा म हस्ता तरिन हा जाती है। इन वक्तिया क प्रयोग नी पर प्रत्यक सविधान म पृथक-पृथक हाती है। प्रत्यक दश म विधिक शक्तिया क हस्तानी म परम्परा एव अभिसमय जिमिन्न मात्रा म जिमातील हात हैं। इसी प्रकार का उदाहरण अमरिका सविधान म ना उपलब्द है। अमरिको राष्ट्रपति का निवर्ति रूरन का विधिक "क्ति राज्य विधानमण्डना द्वारा निर्धारित रोति के अनुसार निर्धाः

निर्वाचक-मण्डल के सदस्यों में निहित होती है। पर तु अभिसमय के फलस्वरूप निर्वा चक मण्डल के सदस्यों की अब अपनी कोई इच्छा नहीं होती। वे अपने दल के राष्ट्रपति पद के प्रत्यादों को मत देने के लिए बाध्य होते हैं। इस स्थिति के लिए अनेक विधिक व्यवस्थाएँ मी उत्तरदायी है पर तु इसमें अभिसमी का महत्वपूण भाग है। एक अ य उदाहरण राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तिया करने की शक्ति से सम्बन्धित है। सीनेटरों के सीज्य के विकास के फलस्वरूण नियुक्तियों के सदभ म व्यावहारिक रूप में सीनेटरों के द्वारा राष्ट्रपति को परामश दिया जाता है जिसकी उपेक्षा करना राष्ट्रपति के लिए कठिन होता है।

(2) परम्पराएँ एव अभिसमय सविधान को एक दूसरे तरीके से भी परिवर्तित करते है। अभिसमयों के द्वारा विधि के अमाव की पूरा किया जाता है। विधि के अनुसार अधिकार या शक्ति किसी व्यक्ति या सस्या को प्रवान की जाती है। वही सस्था उनका प्रयोग भी करती है। अभिसमय उस शक्ति की न तो समाप्त करते है और न हस्ता तरित ही करत है बरन वे उसके उचित प्रयोग की रीति निर्धारित कर देत है। उदाहरणत , विधानमण्डलो को सर्विधान द्वारा विधि बनाने की शक्ति प्रदान की जाती है। विधानमण्टल के द्वारा इस सम्ब ब मे जो स्थायी आदेश (Standing Orders) बनाये जाते है वे सविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति के अभाव को केवल पूण करते है। फ्रांस के चतुर गणराज्य की ससद में समिति व्यवस्था का विकास स्थायी आदेशो सम्बाधी अभिसमय का परिणाम है। स्मरणीय है कि फ्रासीसी शासन व्यवस्था म इस समिति व्यवस्था का विशेष महत्व था क्यांकि फ्रांसीसी मित्रमण्डल की कमजोरी के लिए इस व्यवस्था को काफी हुद तक उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। कुछ देशों मे मिनमण्डलो के निर्माण पर भी परम्पराओ एव अभिसमयो का प्रभाव पडा है। अमे-रिकी राष्ट्रपति को मि नमण्डल के सदस्यों की नियुक्ति सम्बाधी अनियरिनत शक्ति प्राप्त है। पर तुब्बवहार मे वह नियुक्तिया करते समय प्रत्येक महत्वपूण राजनीतिक हित को प्रतिनिधित्व देने का प्रयत्न करता है। ह्वीयरे का मत है कि "इस प्रकार इस अमि समय के द्वारा वह मित्रमण्डल के निर्माण में संधीय तत्व को मा यता दता है।"85 यह अभिसमय आस्ट्रेलिया, कनाडा एव मारत म अधिक मान्य है। आस्ट्रेलिया मे मन्त्रि-मण्डल में प्रत्येक राज्य की प्रतिनिधित्व दिया जाता है। कनाडा के मित्रमण्डल में फ्रेंच एवं अग्रेजी मापाभाषी मि त्रयों के अतिरिक्त क्यूवेक प्रान्त का प्रतिनिधि होना भी आवश्यक है । इसके अतिरिक्त, मिनमण्डल में दूसरे प्राप्तों का एक एक प्रतिनिधि होता है। न्यूवेक एव औटरियो प्रान्तो का करीव करीव समान प्रतिनिधित्व होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभिसमय सविधान की कमी को पूण करते हैं। बनाडा के स्पीकर की शक्तियों की कमी को अभिसमया द्वारा ही पूरा किया गया है।

ह्मीपरे के अनुसार परम्पराओ एव अमिसमयों का हम सविवान से पृचक नही समभ सकते हैं। उनका एक दूसरे पर प्रमाव पडता है। एक के अमाव म दूसरे का प्रभाव नहीं होता है। दोना के मध्य नेवल पतली रेखा गोचना हो सम्भव है और का कभी किमी विधिष्ट मामले के सम्ब घ म यह निषय करना किन हो जाता है कि उन सिवधान के क्षेत्र म रखा जाये अथवा परम्पराआ या अभिसमयो द्वारा उसकी अवस्था की जाय। स्मरणीय है नि जिन वालो नी व्यवस्था एक देश म अभिसमयो द्वारा उसकी अवस्था की जाती है उही के सम्ब घ म दूसरे देश म विधिया को व्यवस्था की गयी है। कभी कभी अभिसमयो को विधिक मा यता देश र सिवधान म सदाोनन करके उसका उप बन दिया जाता है। यावालयो द्वारा मा यता दिय जाने पर भी अभिसमय विधि के कप म मा यता देश किसी विधिक स्थायता हो। विधि के कप म मा यता देश विधिक स्थायता हो। विधि के कप म मा यता देश किसी विधिक स्थायता हो। विधि के कप म मा यता देश विधिक स्थायता हो। विधि के कप म मा यता देश विधिक स्थायता हो। विधि के कप म मा यता देश विधिक स्थायता विधा के कप म मा यता देश विधिक स्थायता विधा के कप म मा यता देश विधिक स्थायता विधि के कप म मा यता देश विधिक स्थायता विधा के कप म मा यता देश विधिक स्थायता विधा के कप मा यता विधा के कप म मा यता देश विधिक स्थायता की स्थायता की मा यता अभी मा यता प्रभाव हो मा विधिक स्थायता हो स्थायता हो स्थायता हो स्थायता हो स्थायता विधा के स्थायता विधा के स्थायता हो स्थायता विधा के स्थायता विधा करा विधा करा करा विधा करा

अन्त म, ह्वीयरे के दाब्दा म अभिसमया के स दम म एक प्रश्न यह है कि सर्वधानिक देशो म परम्पराओ एव अभिसमयो के जिया वयन से सम्यधित क्या कोई सामा य प्रवृति हिंदिगोचर होती है ? इस प्रश्न का उत्तर सरल नही है। एक निरोपता प्राय सभी देशों में अभिसमय के किया वयन के सम्बाध में परिलक्षित होती है। डायसी ने इसका ब्रिटिश शासन सम्ब भी अभिसमयो का उल्लेख करते हुए निम्न शब्दों में उल्लेख किया था। 'अभिसमयो का उद्देश्य निर्वाचक गणो की जो राज्य के वास्तविक राजनतिक सप्रमु है, अतिम सप्रभुता स्थापित करना है।"87 यह कथन अय देशों म अमिसमयो के सावम म सही है। राज्याध्यक्षा के विशेषाधिकार की समाप्ति या सयक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन म निर्वाचक मण्डल के सदस्यों को राष्ट्रपति को निर्वाचित करने में दिसी अधिकार का न होने का अथ केवल जन-इच्छा के माग म भाने वाली वाधाओं को हटाना मान है। इसी सत्य को दूसरे उदाहरण से भी प्रमा णित कर सकते ह । कुछ यूरोपीय देशा मे निपेधाधिकार का प्रयोग समाप्त कर दिया गया है। पर तु अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। क्या ? इसका उत्तर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ब्यवहार म प्रत्यक्ष रीति से ही जनता द्वारा कांग्रेस की तरह चुना जाता है। काँग्रेस की माति राष्ट्रपति भी जन इच्छा को अमिन्यक्त करने का दावा कर सकता है। अमरिकी राष्ट्रपति यदि सविधान की धाराओं के अनुसार अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित होता रहता तो ऐसी स्थिति म उस प्राप्त निर्पेधाधिकार प्राक्ति को यदि समाप्त नहीं किया जाता तो उसे सीमित अवश्य कर दिया गया होता। राप्टपति द्वारा निषेघाधिकार के अविक प्रयोग के नई कारण हो सकते हैं परन्

⁸⁶ Wheare, K C op cit, p 135 87 Dicey Law of the Constitution, (1959), p clu and p 429

प्रत्यक्ष रीति से राष्ट्रपति का निर्वाचन भी इस सादम मे एक महत्वपूण कारण है।
यही नहीं, अप्रिसमयों का क्षेत्र भी व्यापक होता है। वे अत्यवस्यकों के अधिकारों की
रक्षा करते हैं, स्विद्यन्तर्वण्ड एवं कनाडा में दोनों सदनों के मध्य सम्बंधों को
नियमित करते हैं, स्विद्यन्तप्रव्य एवं कनाडा में दोनों सदनों के मध्य सम्बंधों को
नियमित करते हैं, विधानमण्डल के आत्तरिक सगठन को व्यवस्थित करते है एवं
कायपालिका की स्थिति तथा कायपालिका एवं व्यवस्थापिका के सम्बंधों को भी
पर्यान्त प्रमावित करते हैं। वे द्यासन की विधिक सस्थाओं को दलीय शक्ति से सम्ब
नियत करके सासन के स्वरूप को परिवर्तित करते हैं। इससे धासन शक्ति का सावुलन
ही बदल जाता है। अभिसमयों के कारण ऐसे समय में लचीलापन एवं परिवतन
सम्भव होता है जबकि धासनतान में औपचारिक सक्षोजन असामयिक, अनुपनुक्त एवं
धातक प्रमाणित हो सकता है, और विधि मं ऐसे परिवतन अभिसमय के कारण सम्भव
होते हैं जिनकी करणना भी नहीं की जाती। लेकिन अभिसमय की भी अपनी सीमाएँ
हैं। वे सभी बातो को पूण नहीं कर सकते। वे कुछ समय के लिए ही कठिनाइयों को
दाल या कम कर सकते हैं पर जु कठिनाइयों को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते।
यह तो केवल आपचारिक सबैधानिक सक्षोधन या न्यापिक निणयों हारा ही सम्भव है। "

सविधानवाद [CONSTITUTIONALISM]

सिप्पानवाद आधुनिय गुन तो एव महान् उपलब्धि है। राष्ट्रीय एव अन्तर राष्ट्रीय स्तर पर मानवता व समक्ष अनव समन्याएं मृह बाय राष्ट्री है। यदि इता उचित समापान नहीं हुआ तो विनादा वा मय है। सिप्पानवाद इनम स कुछ वा यदि मुलभाने म सफद रहा है तो अनेक ने सदम म अनक्त मी रहा है। सिष्पान वाद समयक एव विराधी दाना हो सवपानिय परियतना से सनुष्ट नहीं हैं और सिंध्यानवाद को उहाने छोछला एव दिवालिया चापित किया है। अनक बार निर्दुध तत्र की स्थापना का प्रयत्न विया गया है और उनने यह प्रयत्न असक्त रहें हैं। इन असक्तताओं से सिव्यानवाद में महत्व वी पुष्टि होती है। आज विनान एव कता ही नहीं, मानवाम मूल्या के विनाध का भी खतरा है। अत सियानवाद का अध्ययन के कल अपक्षित ही नहीं, अपिन्त अनिवाय है।

सिवधानवाद सवधानिय सासन एव सवधानिक राज्य का पर्यायवाची है अमेरिकी विचारक सी जे के ब्रेडिक के अनुसार "व्यक्तियों का विमाजन सम्य सरकार का आधार है। यही सविधानवाद है। स्विधानवाद राजत नीय एव लोकतानीय बेता ही हा सकते हैं। अमेरिका में गणतानीय लोकतान है तो इसकर है ।" अमेरिका में गणतानीय लोकतान है तो इसकर में राजतानीय लोकतान या सवधानिक लोकतान । निरकुशतान का विलोम ही सविधानवाद है। सविधानवाद निरकुशतान के विवद्ध प्रतिक्रिया का परिणाम है। इसल्येष्ड म सविधान वाद विधि के लासन (Rule of Law) का पर्यायवाची है। सासन के अधिकारिये द्वारा व्यक्ति का मनमाने वग से प्रयाग न करना और सत्ता का एक केन्द्र में के कि न होना सविधानवाद के प्रभुत सिद्धात है। निरकुश, अनुसरदायी तथा कन्द्रीहर सत्ता की मध्यपुगीन व्यवस्था एव स्थाम की प्रवर्धि का विधानवाद मेरि दिरोध है। कोकता जनता की सहमति पर आधारित शासन है। प्रस्त यह है कि जनता की सहमति पर आधारित शासन है। प्रस्त यह है कि जनता की सहमति पर आधारित शासन है। प्रस्त यह है कि जनता की सहमति पर आधारित शासन है। प्रस्त यह है कि जनता की सहमति पर आधारित शासन है। प्रस्त यह से कि जनता की सहमति पर आधारित शासन है। प्रस्त यह से कि जनता की सहमति पर आधारित शासन है। प्रस्त यह से कि जनता की सहमति पर आधारित शासन है। प्रस्त यह से कि का सम्य से उसकी अभिध्यक्ति हो। जनशक्ति का लोक हित से जन सहमति से निर्मित विधि

¹ Division of power is the basis of civilized government. It is what is meant by Constitutionalism. Constitutionalism can be monarchial or it can be democratic and it has been both frederick C J Constitutional Government and Democracy (Revised on 1964), p. 5.

अनुसार प्रयोग एव अभिव्यक्ति ही सविधानबाद है। सविधान द्वारा शासन की सीमा एव उसकी शक्ति को नियमित एव निर्यारित किया जाता है। उसकी निरकुशता पर अवरोध (hindrances) की व्यवस्था की जाती है। अत शासन की शक्ति के निरकुश प्रयोग पर प्रतिव ध त्याने वाले नियमा एव सस्थाओं को सामूहिक रूप से सविधानबाद की सज्ञा दे सकते हैं। सविधानबाद शान्तिपूण परिवतन में विद्यास करता है यधिप परिवतन की यह रीति जुछ पैचीया अवस्य होती है। स्मरणीय है कि निरकुशतात का वीधकाल से विरोध होता रहा है पराजु सविधानबाद आधुनिक युग की ही उपलब्धि है। सविधानबाद के विकास की सक्षिप्त रूपरेखा निम्नवत है

प्राचीन सविधानवाद

प्रसिद्ध मुनानी विद्वान अरस्तू न सवप्रथम सवशानिक शासन की परिमापा वी थी। उसके अनुसार सविधानवाद के मुर्प तत्व है—सावजिनक हित, सामाप्य कानूनों का शासन एवं सहमति का आधार। अरस्तू ने प्लेटों से मिश्रित शासन के विचार को प्रहुण किया था। प्लेटों कुत 'वॉज' में मिश्रित शासन की बारणा पायी जाती है। अरस्तू इससे प्रभावित हुआ था और यही आरमा प्रीक इतिहासकार पोलिवियस मं स्थापक रूप से मुजरित हुई थी। पोलिवियस ने मिश्रित शासन की धारणा को एक नया क्ष्य प्रवान किया था। स्मरणीय है कि रोमनो द्वारा वादी बनाय जाने पर पोलिवियस ने रोम मं अनेक वप व्यतीत किये थे। उसने रोमन साम्राज्य की सुहवता एवं स्थायित्व के लिए मिश्रित सविधान को ही उत्तरवामी ठहराया था। रोमन गणराज्य में पोलिवियस के अनुसार काउ सल, सीनेट और लोकप्रिय समा कमश राजतानीय, अमिजात्य-तानीय एवं लोकनानीय व्यवस्था कं प्रतीक थे। सिसेरों ने भी मिश्रित शासन की धारणा की स्वीकार किया है।

रोमन विधि का सविधानवाद के विकास में योग

रामन विचारका की सबसे महत्वपूण दन रोमन विधि एव प्रशासन के सिद्धा त है। रोमन विधि ने ही साम्राज्य में एकता एव के दीकरण को अधिकाधिक सम्मव बनाया था। इसना मुख्य कारण यह था कि सम्मृण मध्य युग एव आधुनिक पुग के प्रारम्भ तक राजाओ द्वारा नियुक्त प्यायाधीशो ने रोमन विधि को ही क्रियाचित किया था। प्ररम्भ यह है कि इस काल से रोमन विधि का पालन क्यों किया जाता रहा ? इसका मुख्य कारण यह था कि दीधकालीन परम्पराओ एव रीति रिवाचों के रूप में स्थानीय विधिया का अधिकाधिक प्रचलन था। इनसे उत्पान गतिरोधों को दूर करने में रोमन विधि सहज रूप में सहायक हुई थी। कालान्तर में रोमन विधिया की सवया मिन ज्यान्याएँ होती रही है जिसस उसके मूल मत्त्र यो भग्मीर अत्तर पड गयं। केकिन रोमन विधि अनेक ऐसे सिद्धा त थे जो नवीदिन व्यावसायिक समाज के अधिक उपयुक्त एव अनुकूल थे। स्मरणीय है कि रोमन विधि विकसित व्यावसायिक समाज की विधिया थी। स्थानीय विधिया अपकाकृत कृष्य प्रथान एव कम सुसस्क्रत समाज की विधिया थी।

सविधानवाद [CONSTITUTIONALISM]

सवियानवाद आधुनिक युग की एक महान् उपलब्धि है। राष्ट्रीय एव जन्तर-राष्ट्रीय स्तर पर मानवता क समक्ष अनेक समस्याएँ मूह वाये खड़ी हैं। यदि हम रा उचित समाधान नहीं हुआ वो विनादा का मय है। सवियानवाद इनमें से कुछ को यदि सुलभाने म सफत रहा है तो अनेक के सदम म जमक्ष भी रहा है। सिवधान वाद समयक एव विरोधी दोनों हो सवैधानिक परिवतना से स तुष्ट नहीं हैं और सिंध्यानवाद को उन्होंने सोसला एव दिवालिया घोषित किया है। जनेक बार निरकुश तान की स्थापना का प्रयत्न विद्या यथा है और उनके यह प्रयत्न असक्त रह हैं। इन असफतताओं से सविधानवाद के महत्व की पुष्टि होती है। आज विनान एव कता ही नहीं, मानवीय मूक्यों के विनाश का मी खतरा है। अत सविधानवाद का अध्ययन केवल अपिसत ही नहीं अधिनु अनिवाय है।

सविधानवाद सवधानिक सासन एव सवधानिक राज्य का पर्यायवाची है। अमेरिकी विचारक सो के फ्रेडेरिक के अनुसार "यहिष्यो का विमाजन सम्म सरकार ना आधार है। यही सविधानवाद है। सविधानवाद राजत नीय एव लोकत नीय योगे ही हो सकते हैं ।' अमेरिका म गणत नीय लोकत न है वो इयलण्ड म राजत नीय सोकत न या सवधानिक लोकत न। निरकुशत न का विलोम ही सविधानवाद है। सविधानवाद है। सविधानवाद निरकुशत न के विच्छ प्रतिक्रिया का परिणाम है। इसलैण्ड मे सविधानवाद है। सविधानवाद निरकुशत न के विच्छ प्रतिक्रिया का परिणाम है। हासलेण्ड मे सविधानवाद विधा के सासन के अधिकारियो हारा विक्त का मनमाने दग से प्रयोग करना और सत्ता का एक केंद्र म केंद्रित न होना सविधानवाद के प्रमुख विद्यात हैं। निरकुश्त, अनुसरदायी तथा केंद्रीहल सत्ता की मध्यपुगीन अवस्था एव प्रयोग की पद्धित का सविधानवाद पोर विरोधी है। सोकत ज जनता की सहमति पर आधारित शासन है। प्रकर वह है कि जनता की सहमति पर आधारित शासन है। प्रकर वह है कि जनता की सहमति पर आधारित शासन है। कन सहभा और साम के प्रदेश में दस्ति किम प्रकार आपत की बाम तथा किस प्रकार और किन सहसात्रा के मध्यप्र है। जनसात्त की सहमति पर आधारित शासन है। प्रकर वह है कि जनता की सहमति किम प्रकार और किन सहसात्रा के साम्यव्य है उत्तकी लिम्प्यपित हो। जनसात्त को लोक हित म जन-सहमति से निर्मत विधि के

¹ Division of power is the basis of civilized government. It B what is meant by Constitutionalism. Constitutionalism can be monarchial or it can be democratic and it has been both?—Frederick C J Constitutional Government and Democracy (Revised edn. 1964) p. 5

अनुसार प्रयोग एव अभिव्यक्ति ही सविधानवाद है। सविधान द्वारा धामन की सीमा एव उसकी शक्ति को नियमित एव निर्भारित किया जाता है। उसकी निरकुशता पर अवरोध (hindrances) की व्यवस्था की जाती है। व्रत शासन की शक्ति के निरकुश प्रयोग पर प्रतिवश्य लगाने वाले नियमा एव सस्थाओं को सामूहिक रूप से सविधानवाद की सज्ञा दे सकते हैं। सविधानवाद शांजिपूण परिवतन में विश्वास करता है यद्याप परिवतन की यह रीति कुछ पेचीदा अवस्थ होती है। स्मरणीय है कि निरनुशत प्रका दीघकाल से विरोध होता रहा है पर जु सविधानवाद आधुनिक युग की हो उपलब्धि है। सविधानवाद के विकास की सक्षित्त रूपरेखा निम्नवत है

प्राचीन सविधानवाद

प्रसिद्ध यूनानी विद्यान अरस्तू ने संवयधम सबैधानिक शासन की परिमापा दी थी। उसके अनुसार सविधानवाद के मुर्य तत्व है—सावजिनिक हित, सामा य मानूनों का शासन एव सहमीत का आधार। अरस्तू न प्लेटों से मिश्रित शासन के विचार को पहुण किया था। प्लेटों हुत 'वॉज' में मिश्रित शासन की विचार को पहुण किया था। प्लेटों हुत 'वॉज' में मिश्रित शासन की धारणा पायी जाती है। अरस्तू इससे प्रमावित हुआ और यही धारणा प्रीक इतिहासकार पोलिवियस में ध्यापक रूप से मुखरित हुद थी। पोलिबियस ने विश्वपत की धारणा को एक नया खप्प प्रदात किया था। स्मरणीय है कि रोमनो द्वारा व दी बनाय जाने पर पोलिवियस ने रोम मं अनेक वप व्यतीत किये थे। उसने रोमन साम्राज्य की सुइहता एव स्थामित्व के लिए मिश्रित सावान को ही उत्तरदायी ठहराया था। रोमन गणराज्य मे पालिव्यस के अनुसार काउ सल, भीनेट और लोकप्रिय सा क्षमश्च राजव त्रीय, अमिजाय व न्त्रीय एव लोकत नीय व्यवस्था के प्रतीक थे। सिसेरों ने भी मिश्रित शासन की धारणा की स्वीक्षार किया है।

रोमन विधि का सविधानवाद के विकास मे योग

रामन विश्वारका की सबसे महत्वपूण देन रोमन विश्व एव प्रशासन के सिद्धार है। रोमन विश्व ने ही साम्राज्य म एकता एव के द्रीकरण को अधिवाधिक सम्मव बनाया था। इसका मुत्य कारण यह था कि सम्पूण मध्य युग एव आधुनिक युग के प्रारम्भ तक राजाओ हारा नियुक्त यायाधीशो न रामन विश्व को ही क्रियाचित किया था। प्रश्न यह है कि इस काल म रोमन विश्व को पालन क्यो किया जाता रहा ? इसका मुख्य कारण यह था कि दीधकालीन परम्पराओ एव रीति रिवाजो के रूप म स्थानीय विश्वया का अधिकाधिक प्रचलन था। इनसे उत्पन्न गतिरोवों को दूर करने म रोमन विश्व सहुज रूप म सहायक हुई थी। कालान्तर म रोमन विश्वयों की सवया मित्र व्यारपाएँ होती रही है जिससे उसके मूल मन्तव्यों म मम्मीर जतर पड यथं। लेकिन रोमन विश्व में अनेक ऐसे सिद्धात थे जा नवीदित व्यावसाधिक समाज के अधिक उपमुक्त एव अनुकूल थे। स्थानीय विश्वया अपेक्षाइत कृषि प्रथान एव कम सुस्सन्त समाज की विश्व-सिद्धा थी। स्थानीय विश्वया अपेक्षाइत कृषि प्रथान एव कम सुसस्त्र समाज की विश्व सिद्धा थी।

रोमन काल मे शासन सस्याओ का विकास तीन अवस्थाओ म हुआ है । रोम का उदय राजतात्रीय नगर-राज्य के रूप मे हुआ था। इस समय शासन ने मुख्य अग थे--निर्वाचित राजा, सीनेट (परामश्रदात्री समिति) और जनसमा या असेम्बली । 510 ई पूम रोम में गणत न का उदय हुआ। गणतन्त्र के अतिगत राजा की सभी शक्तिया काउ सल नामक दो अधिकारिया में अधिष्ठित हो गयी जो प्रति वप निवाचित किये जाते थे। काला तर में अप कुलीनवर्गीय अधिकारी (Patricians) भी शासन सत्ता के प्रयोग से सम्बर्धित हो गये थे। जनसभा (Concilium Plebis) के निणय इन सदस्यो पर बाधनकारी हाते थे । यही जनसमा-असेम्बली-काला तर म रोमन सविधान की एक नियमित विशेषता बन गयी थी। पोलिवियस जिस काल मे रोम म बादी जीवन व्यतीत कर रहा था. उस समय यथाथ मे रोमन गणराज्य म सीनेट का पासन या यद्यपि जसने रोम गणराज्य के स्थायित्व का कारण मिश्रित सर्विधान को माना है। स्मरणीय है कि रोम म यह विचार माय या कि सिद्धातत सभी शक्तिया थ तह जनता से प्राप्त हुई है। सकटकाल म अस्थायी अधिनायकत्व की स्थापना का विधान या और अतिम सही ई प म इटली से न्याप्त गृहयुत काल में अनेक अवसरी पर विजयी सेनापतियों के निरकुश कार्यों को इसी व्यवस्था के आधीन सवधानिक ठहराया गया था। 48 ई पू में जूलियस सीजर वे द्वारा पोम्प (Pompey) का दमन करने पर सीनेट ने अपनी निधिजयता को स्वय अनभव करते हुए जुलियस सीजर को जीवन गर के लिए अजिनायक बना दिया था। इस प्रकार रोमन साम्राज्य का उदय हआर था।

स्ताप के अनुसार रोमन सविधान न प्राचीन काल मे बही भूमिका निर्माई थी जो बिटिश सविधान ने आधुनिक गुग मे निर्मायों है 1⁸ जेस्स बाइस के अनुसार रोमन साम्राज्य का सगठन उन सभी सस्थाओं पर आधारित था जिनका विकास लघु गणराज्य काल मे हुआ था। रोमन सविधान की कुछ मीसिक विशेषताएँ निस्नवत है

1 रोमन सिवान बिटिश सिवान की भागि परम्परात्रो, स्मृतियो, रीति रिवाजो, अभिसमया, विश्वासी एव वकीला तथा राजनीतिनो के तथा मे उपलब्ध या।

इनका स्पष्ट शब्दो म बोई उल्लेख नही था।

² The importance of Rome in the history of Constitutionalism lies in the fact that its constitution played in the ancient world a part comparable to that played by the British Constitution in the modern world '-Strong op at, p 18

है। इस काल म रोमन सविधान म जनक परिवतन हुए थे। रोम प्रारम्भ म नगर-राज्य, फिर गणराज्य एव जात म साझाज्य बना था। रोम के विस्तार के साथ उसका गणराज्यीय सविधान उसकी जावश्यकतात्रा नी पूर्ति नहीं नर सका। रोम में यूनानी नगर-राज्या की चाँति प्रत्यक्ष लोकतत्र था और प्रतिनिधित्व की धारणा का वहां सवया अनाव था।

- 4 रोमन साम्रानीय यक्ति का सिद्धात सम्राट थस्टीनियन के द्वारा समृहीत सिहिताझा (Institutes एव Digest) पर आधारित था। इस सिहिता के अनुमार सर्बोच्च विधि निर्माण शक्ति जनता में अिथिन्द्रत थी। राजा को जनता द्वारा अधिकार प्रदान किय गये थे। लेनिन जनता द्वारा हर एका को विधिवत अधिकार प्रधान नहीं मिये जाते थे अपितु यह माना जाता था कि हर नथ राजा को पर प्रहुण करने पर अधिकार जनता द्वारा ही प्रवत्त किय जात है। जनता की शक्ति को हिनिहास में विधिवत कभी सी समान्त घोषित नहीं किया यथा अपितु दीधकाल तक प्रयोग निक्य जाते के नारण यह शक्ति निष्प्रमाची ही गयी थी। सभी सम्राट इन धारणा के कारण केवल वण्डाधिकारी थे। काला तर में सम्राट म ही सभी शक्तिय सपित हो। गयी थी। सीन स्वप्रित स्वपित हो अधिकार करने वाला अग) साम्राज्य के अतिम काल में कमजोर हो गयी थी और सम्राट नी इच्छा को स्थीकृत करने वाली सस्मा मान रह गयी थी।
 - स्ट्राग के अनुसार रोमन सविधानवाद के स्यायी प्रसाव निम्नवत है 3
- 1 रोमन विभि ना महाद्वीपीय यूरोप के विधिक इतिहास पर गम्मीर एव ब्यापक प्रमाव पड़ा है। रोमन साम्राज्य के अत के बाद पश्चिम के द्यूटोनिक आक्रमण-कारियो की प्रथाएँ एव विधिया रोमन सहिता के साथ एकाकार हो गयी थी। फल-स्वरूप यूरोपीय महाद्वीप म विभिक्त पद्धतियो का विकास हुआ।
- 2 व्यवस्था एव एकता की सुदृढ भावना के प्रति रोमनो मे विशेष अनुराग या। फलस्वरूप मध्य युग की विषदनकारी स्थिति म भी राजनीतिक एकता की मावना इंढ बनी रही। रोमनो की इस व्यवस्था एव एकता की मावना मे युद्ध को रोकने हेतु जन्मरीष्ट्रीय सत्ता की स्थापना सम्बंधी आधुनिक उदारवादियों के स्वप्न निहित है।
- 3 सम्राट की विधिक सत्रभुता सम्ब धी दुहरी सकल्पना कई शताब्दिया तक जारी रही जा शामक तथा शासितों के मध्य दो मध्ययुगीन धारणाओं के लिए उत्तर-दायों है। प्रथम, सम्राट की इच्छाएँ ही विधिया थी। दितीय सम्राट की शक्तिया जनता में निहित हैं और अतत जनता से ही थे सम्राट की प्राप्त है। मध्य पुग के प्रारम्म में पहली धारणा जनता द्वारा राजाआं के पूणकर्षण पालन का आधार वनी एवं मध्य पुग के अत में इस दितीय धारणा ने इस सिद्धात का जम्म दिया कि जनता को साग्रट की शक्तिया प्राप्त करने वा अधिकार है। अधुनिक काल में यही धारणा लोगत व का वाधिनिक आधार है।

मध्य युग मे सविधानवाद

मध्य युग का प्रारम्भ 410 ई म रोम म रोमन साझाज्य के पतन के पश्चात अरम्म होता है। रोमन साझाज्य इसके वाद पूर्वी यूरोपीय प्रदेशा में बना रहा और पूर्वी रोमन साझाज्य की राजवानी कुस्तु जुनिया थी। इसे बाई-जेटाईन साझाज्य की सना भी दो जाती है। पश्चिम को बबर जातियों ने रोम साझाज्य पर आक्रमण प्रारम्म कर दिये थे। विसीगोधो (Visigoths) ने रोम को 410 ई म ध्वस्त कर दिया था, फल स्वरूप पश्चिम से रोमन साझाज्य का बात हो गया। पूर्वी रोमन साझाज्य का 1453 ई म तुक आक्रमणकारियों द्वारा अत कर दिया या। यह एक हजार वय का काल मध्य युग कहानाता है। बबर जातियों के आक्रमण के कारण रोमन राज्य की एक रोमन विधि की सावभौमिनता खण्डित हो गयी। पर तु विश्व राज्य की विधिक धारणा ययावत बनी रही और इसी पर पविन रोमन साझाज्य का विकास हुआ।

पवित रामन साम्राज्य की स्थापना 800 ई मे चालिमेन ने की थी। यह रोमन साम्राज्य से सबया मिन सगठन था। इसमे रोमन सविधान का पूण जमाव था। 9वी एवं 10वी सदी के जाकमणो तथा चालिमेन की मृत्यु के बाद उत्तरा धिकारिया के मध्य साम्राज्य के विशाजित हो जाने के कारण यह साम्राज्य विषटित हो। गया और पुन उस गौरव को वह कभी प्राप्त न कर सका जो चालिमेन के समय में उसे प्राप्त था।

साम तबाद मध्य युग की अनिवाय विशेषता थी। स्ट्राय ने साम तबाद को प्रारम्भिक मध्य युग की अराजक स्थिति एव आधुनिक राज्य की व्यवस्था के मध्य सेतु की सजा दी है। साम तबाद के अ तगत समी भूमि इकाइया म विमाजित थी। राजा और जा क मध्य में साम तबाद के अ तगत समी भूमि इकाइया म विमाजित थी। राजा और जा क मध्य में साम त वग था। साम तो को अपनी जागीर में निवास करने वाली प्रजा पर पूण अधिकार थे। साम त एव प्रजाजनों के सम्ब घ स्वामी व दास के सम्ब थे थे। इत सम्ब धो की प्रज्ञां तथे शत्या पर पूण अधिकार थे। साम तवादी समाज के निश्चे समाज की अपेक्षा विके द्वित समाज था। स्ट्राय ने साम तवादी समाज के निश्चे सामाजिक एव राजनिक सगठन था। भी रोमा तक व्यवस्थित तथा सामायत स्थित सामाजिक एव राजनिक सगठन था। भी रोमा तथा दिस्ता की निष्कुत सत्ता प्रदान की विकेत सगठन था। भी रोमा पर पर चाक्ति सामायत स्थित सामाजिक एव राजनिक सगठन था। भी रोमा पर पर चाक्ति हो सिमा सी थी। साम तवाद इसका एक प्रमुख कारण या कि त अय कारण चिन्नवत थे

(1) यक्तिशाली चच का विकास । चच एव राजसत्ता के मन्य समय मध्य युग

^{4 &}quot;Feudalism seems to have been an inevitable growth to bridge the gulf between the chaos of early medieval times and the order of the modern state. He further says that Feudalism "was a kind of medieval constitutionalism since it was to some extent systematised into a generally accepted form of social and political organisation."—Strong, C. F. op. att. p. 24.

को महत्वपूण घटना है। इड धार्मिक विश्वासो ने चच की सत्ता की वृद्धि म योग दिया या और चच ने लोक्कि एव पारलौकिक दोनो ही क्षेत्रा म सत्ता का दावा किया या।

(2) अनेक स्वतंत्र राज्यो और स्वतंत्र गणराज्या का मध्य युग म विकास

हुआ था।

उपयक्त कारणा के परिणामस्वरूप मध्य युग म राजनतिक एकीकरण की प्रवृत्ति मुखरित न हो सकी और न ही उसका जन्म हा सका। पर तु मध्यपुगीन विचारो म आधुनिक सविधानवाद के निम्नलिखित बीज अवश्य अकुरित हुए थे

(1) सबन्यापी विधि की धारणा।

(2) लोकप्रिय प्रभुत्व का तिद्धाल—इस सिद्धाल्त की स्पष्ट व्यारया मध्य-युग म नहीं हुई थी परतु इसे इस युग म महत्व अवश्य प्राप्त हुआ था। रोमन विशि म तोकप्रिय सप्रभुता की धारणा स्पष्ट रूप म समाबिष्ट थी। मध्य युग में एक्कि निकाय (Corporate body) नी धारणा और उसके स्पष्ट अधिकार एव कर्तव्य की यारणा का पूणत्या विकास हुना। पेडुआ निवासी मासींसियो न वोषणा की थी कि "जतता की आवाज ही ईश्वर की आवाज है।"

(3) प्रतिनिधि शासन की धारणा का प्रारम्भ भी मध्य युग म हुआ था। मार्सीलिया ने राजनैतिक समुदायो के अतिरिक्त मध्ययुगीन चच के सगठन के लिए भी प्रतिनिधि धासन के सिद्धान्त का प्रतिगादन किया था।

कन्द्रीकरण नी प्रवृत्ति का विकास सवप्रथम पश्चिमी यूरोप के देशा, विशेषकर इगलैण्ड, फास और एक सीमा तक स्थन म 11वीं सदी म प्रारम्म हुआ था जिसके परिणामस्वरूप सामातो की शक्ति को अतत नष्ट कर दिया गया था। राष्ट्रवाद एव प्रतिनिधि लोकतान की धारणा का भी सबप्रथम विकास इही देशा म हुआ था। स्ट्राग राष्ट्रवाद एव प्रतिनिधि शासन को आधुनिक सविधानवाद के प्रधान नक्षण मानता है। इगलण्ड एव फ्रांस म पोपशाही विरोधी धारणा का विकास हुआ था। दाना देशा में राष्ट्रीय चच की स्थापना हुई एव दोनो ही देशा म समाज की विभिन जागीरा (estates) के प्रतिनिधियों की समाएँ आयोजित की गयी थी। इंगलण्ड मंइस प्रकार की प्रतिनिधि समा का उदाहरण 1265 ई की प्रथम ससद (Long Parliament) थी जिसमें शाइरा (shires) के साम तगण एवं नगरी के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। भास में प्रथम संसद का अधिवंगन 1302 ई में आयोजित किया गया था। 100 वर्षीय युद्ध (1337-1453) न इन दोना देशो—इगलैण्ड एव फा स—म राप्टीयता की भावना को और अधिक विकसित किया था। स्पन म राष्ट्रीयना के उदय के लिए विरोप परिस्थितिया उत्तरदायी थी । 8वी सदी म स्पेन के अधिकाश भाग पर मुसल-मान मुरो ने अधिकार कर लिया था। अल्पसंख्यक ईसाई समाज ने इन विधामिया का एक होकर मुकाबला एव विरोध किया। 14वी सदी म स्पन मे दो मूख्य राज्य-आरगान (Aragon) एव सेस्टील (Castile)-थे। इन दीना राज्यो म गावा एव शहरों के प्रतिनिधियां की प्रतिनिधि समाएँ थी जि ह कारटीस (Cortes) यहा जाता

था। इन दोनो राज्या म नवाहिक सम्बन्ध स्थापित होने के कारण 15वी सदी के अ त मे दोनो राज्य एक हो गये। जमनी एवं इटली म इन राज्या की अपक्षा अधिक समय तक साम तबाद का बोलवाला बना रहा । चच एव साम्राज्य के अधिकारिया के मध्य होने वाले सघप ने स्थिति को और अधिक विगाड दिया था। मध्य-पूग की दो मूर्य सस्थाएँ-चच तथा पवित्र रोमन साम्राज्य-13वी सदी तक इतनी कमजीर हो चकी थी कि उनके पुनर्जीवित होने की कोई आजा श्रेष नहीं रही थी। इस अरा जब स्थिति से बचने का उपाय चच की प्राचीन सस्था-सामान्य परिपद (General Council)-के पुनरुद्धार के प्रयत्न द्वारा किया गया था और पोप को इस सामाय परिपद के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था । यह प्रयत्न परिपदीय आ दोलन (Con ciliar movement) वहलाता है। 1409 ई म पीसा की परिपद (Council of Pisa) एव 1414-18 ई में नास्टेस की परिषद (Council of Constance) आयोजित की गयी थी। का स्टेस की परिवद से पाटरी एवं गर पादरी दोना ही प्रति निधियों ने भाग लिया था और पोप पर परिषट के स्थाधी नियन्त्रण का विधान निया था । यह व्यवस्था असफल रही । 1431-39 ई की बासील की परिपद (Council of Basel) के बाद से चन की परिवदीय व्यवस्था यद्यपि लप्त हो गयी थी परन्त चन के परिपदीय आदोलन का सविधानवाद की इंटिट से विशेष महत्व है।

स्ट्राग ने इसके निम्नलिखित दो महत्वो का उल्लेख किया है "

(1) विभिन्न परिपदी में स्वीकृत नाय पद्मित एवं संगठन के यह स्पष्ट है। गया था नि यूरोप में होने वाले राष्ट्रीय विभाजनों को स्वीकार कर लिया गया है। का स्टेंस की परिपद से राष्ट्री के लिए सर्वधान का आवार अपनाचा ज्या था और पा

राष्ट्रीय समूह)—इटालियन, फ्रेच जमन अर्थेज एक स्पेनिश—को माण्यता दी गयी थीं। (2) इस आंदीलन ने इस सम्बन्ध मं प्रस्तावित अनेक उपायी पर विचार

(2) इस आ दालन न इस सम्बन्ध में प्रस्तावित अनक उपाया पर । विकार की साथा पर । विकार की साथा परिपद में पादियों के अतिरिक्त समस्त ईसाई मती वलियम को किस प्रकार प्रभावशाली ढण से प्रतिनिधल प्रदान किया जाये । इन प्रयत्नों के फलस्वरूप 15वी सदी म मासांतियों, ओक्स निवासी विलियम, जॉन जमन एव बूसा निवासी निकोलस के राजनतिक विचारा का उदय हुआ जिहोंने बंधापक रूप से अनेक राजनतिक समस्याओं—जैसे सम्रभुता, राष्ट्रीयसा, प्रतिनिधित्व एवं राजत त—आदि प्रकार पर अपने मत द्यक्त किय और आधुनिक युव के मानी सवधानिक विकास की करणना की।

आधुनिक सविधानवाद

मध्य-युग के बाद विकास की हस्टि से सविधानवाद की निम्म अवस्थाएँ मानी जा सकती है —(1) पुनर्जागरणकालीन राज्य, (2) इसलैण्ड म सविधानवाद , (3) अमेरिना एव फ्रेंच ऋतियों का सविधानवाद पर प्रभाव, और (4) राष्ट्रीय सवि धानवाद ।

⁵ Strong C F op cst, p 26

पुनर्जागरणकालीन राज्य

15वी शताब्दी पूनजागरण काल की शताब्दी है। यूनानी विचारो के पुनरूत्थान के फलस्वरूप मध्ययुगीन मा यताजा एव विश्वासो के जा गर को जड़े हिलने लगी यी । प्रमाणवाद (Authoritarianism) को शका की हिन्ट से देखा जाने लगा था । बृद्धिवाद (Rationalism) का उदय हुआ था। घम सुवार आ दोलन इसका पहला परिणाम था । युनानी ज्ञान के पूनरुत्थान के दो सामा य राजनतिक परिणाम हुए थे प्रथम, मध्ययुगीन सावभौमिकताबाद के विपरीत आणविक पृथकता की प्रवृत्ति का विकास , एवं द्वितीय, प्रथक प्रथक राज्यों का एकीकरण । राप्टीय दृष्टि से इंगलण्ड, फ्राप्स एव स्पेन अब एकीकृत राज्यों में समिठित हुए। जमनी एवं इटली में भी एकीकरण की प्रवृत्ति सिक्य हुई थी पर तुसीमित क्षेत्रों के फलस्वरूप इन देशों म अनेक राज्या का उदय हजा। स्ट्रांग का मत है कि अनेक अर्था में पुनर्जागरण न उस अच्छे काय को समाप्त कर दिया जो कि तीन पश्चिमी राज्या मे प्रारम्म हुआ था। पुनर्जागरणकालीन राज्य सच्चे अयों मे सर्वधानिक राज्य नहीं थे, उ ह प्रजात नात्मक राज्य तो कहना ही नहीं चाहिए । उनकी मूर्य विजेपता बाह्य सप्रभुता थी जिसका अब एक सहुद के द्रीय सत्ता की स्थापना थी जिससे कि राज्य हर प्रकार अपनी रक्षा विशेषत अपने पडोसियो से कर सके। अत मुख्य उद्देश्य राज्य की शक्तिशाली बनाना था। इसरणीय है कि इस युग म यूनानी स्वायत्तता या स्वतात्रता की बारणा लोक-प्रिय न हो सकी। राज्य सत्ता व्यक्तियों के अधिकारों के बारे मे चितित नहीं थी। स्ट्राग के अनुसार पुनर्जागरणकालीन सम्राट नीतिशास्त्र (ethics) या नतिक वातो की जपेक्षा राजनीति से अधिक सम्बर्धित थे। स्मरणीय है कि मैकियाबली द्वारा 1513 ई मे रचित पुस्तक 'त्रि स' (The Prince) इसी ह्प्टिकोण का प्रतिपादन करती है। मिकयावली पुनर्जागरण का शिशु था। सक्षेप मे, इस काल में राज्य पर किसी नितक अश्वि घन की व्यवस्था का समयन नहीं किया गया था क्योंकि उससे राज्य की सत्ता के कमजीर होने की आशका थी।

16 में सदी के धम सुवार आ दोलन ने पुनर्जागरणकालीन राज्य को दबीय मायता प्रदान नी। मादिन ल्यर धम सुधार आविलन का नेता था। यह धार्मिक मामलो म पूण सहिष्णुवा एव स्वत नता का समयक था। लेकिन पाप से अपनी एव अपने समयका नी रक्षा के लिए उसे किसी राजा की सहायता की अपेक्षा थी। यह सहायता उसे ते सहस्ता के इंदोलटर्र से प्राप्त हुई थी। सेक्सनी के शासक ने रोमन चच से पूपक अपना चच स्थापित किया। यह चच रामन चच की माति ही असहिष्णु था।

^{6 &}quot;But in many respects the Renaissance undid the good work that had been going on in the three western states. The Renaissance state was not truely constitutional, much less a democratic state. Its essential equality was external sovereignty, which implied a strong central authority maintaining itself at any cost, chiefly with a view to strengthening the state against all its neighbours.—Strong op ctt, p. 27

लूबर द्वारा पोपशाही ने विरुद्ध प्रस्तुत सैदातिक तनों के परिणामस्वरूप सम्राट या राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुई और उन्हें अपनी जनता के धार्मिक मामला ना निय मित करने की शक्ति प्राप्त हो गयी। यह प्रवृत्ति इमलण्ड म भी परितक्षित हाती है। हेनरी अल्टम, ऐतिजावेष प्रथम एव जेम्स प्रथम को धार्मिक मामला म भी मर्वोज्वता प्राप्त थी।

अत स्ट्राम का मत है कि पुनर्जागरण-नाल म राज्य की सप्रभुता की धारणा ने मन्य युग के अत स पिर्विमी पूरीए म रोष गय सवैधानिकता के बीज का पल्लियत एव पुण्यित होने म जबी बाधा डाली थी। यूरोपीय महाद्वीप पर प्रबुढ निरकुत्तत भीय राजवन्त (Enlightened Despotism) विक्षित हुआ। इसका काल 1600 ई से 1789 ई तक है। फान्स, प्रवा (Prussia) एव आस्ट्रिया म यह निर कुशतन पूणता को प्राप्त हुआ था। सामतवाद के पतन के याद सम्राट या राजा ही सत्ता का के द्र था। सम्रादा वाद के पतन के याद सम्राट या राजा ही सता का के द्र था। सम्रादा हारा प्रतिनिधि सस्थानों का सहयोग साल करवोग म नहीं लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप महाद्वीधीय देवो म सविधानबाद का विकास 19वी दाताब्दी तक रका रहा। केवल इसलेण्ड म ही पुनर्जागरणकालीन राजवन्त निरकुदातन म परिवर्तित नहीं हो सका था। थ

इगलण्ड मे सविधानवाद

स्ट्राग के अनुसार इगलण्ड मं सविधानवाद का अविरत्स विकास हुआ है। इग लैण्ड में भी निर्फुशत न था पर तु पुनर्जागरणकालीन इगलण्ड के राजा अनियिण्ड एव निरकुश न रह सके थे। इसका कारण इगलण्ड की अपनी विचित्र कठिनाइया थी। कास से से पोश्नालीन युद्ध के कारण इंगलण्ड की आर्थिक स्थिति खराब हो गयी थी और गृह युद्ध के कारण देश का विधटन हो गया था।

इंगलण्ड मे प्रतिनिधि सस्या ने रूप मे ससय की सवप्रथम स्थापना 1265 ई म हुई थी। 1295 ई के बाद निरत्तर कुछ जतर से ससद के अधिवेधन आहुत हीतें रहें थे। इस समय ससद का मुख्य काय राजा के लिए धन स्थीकृत करना था। 14शें दाताबंधे के अन ससद का मुख्य काय राजा के लिए धन स्थीकृत करना था। 14शें दाताबंधे के अन म ससद की महत्ता में एक अप कारण से भी बृद्धि हुई थी। 1339 ई म लेकेस्टर वशीय एडवड तृतीय ने रिचड तृतीय स बरवद सिहासन हत्त्तात कर लिया था। परिणामस्यरूप हेनरी चतुण एव उसके उत्तराधिकारिया ने अपने काय की जीचियता प्रदान करने के लिए सबद पर निमर रहना प्रारम्भ कर दिया था। लेकिन हेनरी पठन् की अग्रोग्यता एव मुलाबों के युद्ध म उसकी असफलता के कारण वेनस्टर वसीय शासकों की स्थित और भी कमजोर हो गयी। नये शासक एडवड चतुथ को युद्ध कायम रखना पडा। 1485 ई मे हेनरी ट्यूबर द्वारा रिचड तृतीय को पराजित कर देने पर ही मुलाबों के युद्ध का जत हुआ और ट्यूबर वश के शासन की स्थापना हुई जिसे ट्यूबर निरकुशन न नहां जाता है। वेकिन ट्यूबर बा के शासन की स्थेखाचारिया मुरोभ के तकालीन निरकृत शासनों की विभेशा यहत मुख्य सी स्थ

⁷ Strong C F op cut, pp 28 29

यी। राजा की कायपालिका शक्ति का प्रयोग एक समिति (council) द्वारा किया जाता था जिसकी स्वेच्छाचारिता पर ससद एव यायाधीशा (Justices of Peace) का अकुश था। स्मरणीय है कि ट्यूडर वाल के शासको न विभिन्न ससदो के समक्ष विभिन्न विधायी एव कर प्रस्तावो को स्वीकृति के हेतु उपस्थित विधा था, यह दूसरी वात है कि ससदो के द्वारा उह विना किसी वाबा के ही स्वीकार कर लिया हो। टयूडरकालीन ब्रिटिश ससदे अधिकाशत राजा के आधीन थी। एक महत्वपूण तथ्य यह है कि ससदो के निरत्तर अधिवैशन होते रहते ने एव उनके द्वारा प्रस्तावी को स्थीकृत किया जाताथा। जब टयूडर शासको द्वारा राष्ट्र की इच्छा का प्रति निधित्व करना बाद कर दिया गया तो ब्रिटिश ससद ने उनके विरुद्ध निद्रोह कर दिया था। स्टुअट वशीय चाल्स प्रथम न ससद की उपेक्षा करत हुए ससद की सत्ता का स्वय प्रयोग किया था। फलस्वरूप इगलण्ड स 1642 ई स 1649 ई तक गृह युद्ध हुआ। इस गृह युद्ध ने प्रबुद्ध निरकुशत न की स्थापना में वाधा उत्पन्न की थी। 1649 ई में चाल्स प्रथम का शीश काट दिया गया और कामवेल के नेतृत्व मे गण-राज्य- कॉमनवेल्थ-की स्थापना हुई । 1660 ई में पून राजवान की स्थापना हुई और चाल्स द्वितीय एव जेम्स द्वितीय, जो राजत न की पुनस्थापना के पश्चात कमश सत्तारूढ हुए थे, ने एक बार फिर मिर उठाया था पर तु 1688 ई की रक्तहीन जाति ने जिसे Glorious Revolution की सज्ञा दी जाती है, स्वेच्छाचारी राजत न को उखाड फका। इस जाति से दो महत्वपूण तथ्य स्पष्ट हो गये। प्रथम, शासन सम्ब धी मामली पर नियानण राजा के हाथा से निकलकर राजा सहित ससद (The King in Parliament) के हाथों में पहुँच गया। द्वितीय, जाति के कारण हुए परिवतन को सबै धानिक आधार प्राप्त हुआ । स्मरणीय ह कि इसके पूत इगलण्ड म कोई सबैनानिक सर्विधि (Statutory law of the constitution) नहीं थी और ब्रिटिश सर्विधान केवल प्रथाओ एव अभिसमयो पर ही आवारित था। मेगना कार्टा (Magna Carta) भी सविधि नही था और साम ती यूग के समाप्त होने के पश्चात उसकी व्यवस्थाएँ अन्यावहारिक वन चुकी थी। इसके विपरीत, 1628 ई की पिटीशन ऑफ राइट्स (The Petition of Rights) राजा द्वारा स्वीकृत किये जाते के फलस्वरूप सर्विवि बन गयी थी यद्यपि उसकी व्यवस्थाओं का पालन नहीं किया गया था। कॉमनवेल्य के अन्तगत लिखित सविधान का निर्माण हुआ या लेकिन राजतन्त्र की स्थापना के परचात इन लिखित सर्विधानो का स्वत ही अत हो गया था।

सन् 1688 89 ई की क्रांति के समय पारित अनेक सविधिया के परिणाम-स्वरूप बिटिश राज्य की सप्रभुता बिटिश ससद म निविवाद रूप से अधिन्दित हा चुकी यो। विक ऑफ राइटस, अधिकार-पन एव विद्रोह अधिनयम (Mutnay Act) ने त्रिटरा ससद को सेना पर नियानण प्रदान किया तथा वार्षिक ब्यय की स्वीहृति वी प्रणाली द्वारा निरकुशत त्र पर प्रभावकारी नियानण स्थापित कर दिया था। विचिन कायपातक दायित अभी भी राजा एव उसके मन्त्रियों के हाथा में ही थे। 18थी सदी म अभिसमया के विशुद्ध विकास वे फलस्वरूप दलीय व्यवस्था पर आधारित मित्रमण्डलीय पद्धति का विकास हुआ जो सदी के अत तक पूरी तरह सुदृढ हो चुकी थी। इससे ससद वी शक्तियों म वृद्धि हुई और उसका कायपासिना पर निय प्रण स्थापित हो गया।

प्रशिक्ष के स्वाराज्य के स्वाराज्य पर नियं येण स्थापत हो गया। इंगलेण्ड म निरङ्कत न वे विकास म उसकी भौगालिक स्थिति मी एक वाधा है। द्वीण होने वे कारण निरक्तर वाह्य आत्रमण की कोई सम्मावना नही थी। इस सम्मावना ने अय यूरोपीय देवा म निरङ्कत न के विकास म काणी योग दिया था। इंगलण्ड मे इसके विचरीत निरङ्कत राजत न एव स्थानीय स्वतासकी परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के मध्य सम वय हुआ है। महाद्वीप से पृथक होने के कारण इंगलेण्ड मे राष्ट्रीयता की मावना सदाक्त हुई। इसे दो घटनाजा न अत्यिष्क कारण इंगलेण्ड मे राष्ट्रीयता की मावना सदाक्त हुई। इसे दो घटनाजा न अत्यिष्क अध्यक्षता पोष से विटिश्व सम्राट को हस्ता तरिक कर दो गयों थी। इससे इंगलण्ड मे पोषाहों के हत्वदेष का अत्य हो गया। दितीय, स्पेनिय आर्मेंडा (जहाजी वेडा) की पराजय के बारण ब्रिटिश ससद देश पर बाह्य आत्रमण की सम्मावना से पूणतया मुक्त हो गयी थी।

इसी वाल से इमलण्ड में विधि के वासन (Rule of Law) का भी विकास हुंगा जो ब्रिटिश विधि व्यवस्था का प्रमुख सिद्धा त वन गया। वाद म यह सिद्धा त जपनिवेदा, स्वशासित जपनिवेद्या एव सयुक्त राज्य अमेरिका की विधि-व्यवस्था का मी अधार वना। विधि के शासन का अध विधि के समक्ष विना किसी नेदमान के सभी नागरिका की समानता से हैं। समय समय पर पारित सिविध्य एव प्यायिक निजयों से इस सिद्धा त की स्थापना हुई है। जवाहरणाथ, व दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus, 1679) एव एक्ट ऑफ सेटिलमेंट (Act of Settlement, 1701) द्वारा जहां एक तरफ नागरिका नो गलत दंग से व दी वानाये जाने से मुक्ति प्रवान की धी वहां पायाधीशों को भी शाही हस्तक्षेत्र से मुक्ति प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार, पायिक विवान जैतन विलक्त विवाद (1763)—द्वारा नागरिको को अनुधित रीति सं व दी नानाने एव मिन्या ने सामा य विधि यवस्था के आवीन होने की व्यवस्था का निवारण किया ग्राप्त श्राप्त श्राप्त ।

स्हुम के अनुसार 18वी सदी ने मध्य तन इमलब्ह में सवधानिक धासन की स्वापना हो बुकी थी। उस समय यह विश्व का एकमान सर्वेशानिक राज्य भा पर दुं पूण प्रजात नात्मक राज्य नहीं था। 19वी सदी में ब्रिटिश सबद द्वारा प्रतिनिधित्व सम्बन्धी विमिन्न विधियो—यवा, 1832, 1867 एवं 1884 ई के सुधार-अविनिधमो—ने पारित होने पर ही प्रजात न नी स्थापना हुई थी। 1918 एवं 1928 ई में स्तिया को भी मताधिकार प्रदान निया गया। ब्रिटेन का सब्वानिक विकास कं य देशों ने लिए उदाहरण है। निटिश्य सविधान नी अपनी प्रमुख विश्वेषता उसका अभिसमयो एवं परापराजा पर आधारित होना है। यह विकास का परिणाम है। निटिश सविधान पूत्र निश्चय के जनुसार निर्मात लेल्य नहीं है। नवीन सविधान

बार दात मिन्न है। नबीन सिवधान लिपित होत हैं। बिटिंग सिवधान विषास का परिणाम हो। र रारण अव को नवीन परिस्थितिया रे अदुरूप सहन्न ही बाल सका है और अपनी मोलिकता का परिवर्तित किय विना लिपित सिवधान। र नबीन तत्वा को सप्तरतापूषक अभोगर कर महा है।

अमेरिको एवं फाँच प्रान्तियां तथा उनका सवपातिक प्रभाव

पामिन अमहिष्मुता म एक प्रकार त स्थायी माथा। ता प्रायस्य होता था। थम गुपार वे विकार के सामिक क्टरन्त तथा उत्पाद का बाद उपचार नहीं बर सर थे। पुत्रवारण-नात म राज निक्र अस्थानार भी बढ़े थे। दत परिस्थितिया के न्वारण विकार के कि कि अस्थान कि अस्थान की कि माणाजिन अनु प्रधा सिद्धान्त ना प्रतिभावत कि सामाजिक का अनु य के विकास माणाजिन अनु प्रधा गामाजिक अनुवापवादी विचारत राज्य ना अनु य के परिणाम मानते हैं। यह अनु प प्राहतिक अनस्या को असहाय परिस्थितियो के कारण तरकालीन व्यक्तिया में विचा था। अनु प्रपा के सम्बान्त कि सिंग की स्था के अधिवादा को परिस्थान कर दिया और सम्य समान के लिए आवस्यन सामाप्य सत्ता का निर्माण विचा। अस राजनिक समाज या राज्यका उद्देश व्यक्तिया में विध्य अधिवादा के अनु परना एव उनकी रक्षा की प्रतिमु बना था। सामाजिक अनु व के मिद्धा के अस्था राज्य मानव निर्मित सस्या है एव अनु प के परिणाम है। अत राज्य हारा अस्य पारी होन पर यह अनुवाय के अग परन का अपराधी ही जाता है और एस राज्या के सदस्या वो सामान को पदच्युत वरन पा अधिवार स्वत् ही प्राय्त हो जाता है।

सामाजिक अनुव प सिद्धान्त प्रधानत 18 वी सदी म सर्वाधिक लानप्रिय था। इसने योज यूनानी विनान म भी है। प्लटो द्वारा रचित रिपब्दिन म भी इसका प्रतिपादन हुआ है। मध्य युग म भी इस सिद्धान्त ना चच एव राज्य के विवाद न मध्य प्रतिपादन हुआ था। आधुनिक युग म इसके प्रथम सम्पर्क फास के ह्यूगोनाटस एव स्न के आपीन नीदरलण्ड के निवासी थे जो उपयुत्त वर्णित राजनीतिक जराज कता एव धार्मिक असहिष्णुता के अत्यावारा के दिवनर थे। अनुवाप सिद्धान्तवादिया ने निरकुशता के खण्डन को उचित माना और पीडित व्यक्तिया द्वारा विद्रोह करना उचित ठरामा।

हा स, लाक एव क्या अनुव य सिद्धात ने प्रतिनिधि विचारक माने जाते हैं। तीना के निष्कप एक दूसर से मित्र है यद्यपि तीनो ही राज्य को अनुव स का परिणाम मानत थे। हॉट्स का राज्य निरमुख या स्थोकि बासन अनुव य ना एक पक्ष नहीं था। ताक सीमित राजत न या जनता द्वारा सम्पित शासन ना समयक था। उसन व्यक्तिया के प्राकृतिक अर्थात अनुल्लाभीय अधिकारा पर बल दिया है। लॉक ने 1688 ई म अपेजी प्रात्ति का समयन किया था। यह ह्विम दल का दाशनिक विचारक था। स्सो ने लोकतान एव सम्भुता में अपन अनुव च के द्वारा सम वय स्थापित किया है। हॉब्स

⁸ Strong, C T op cat, p 33

ने स्वत तता एव सत्ता के मध्य समावय करते हुए जनता को विद्रोह का अधिकार नही दिया । लाक ने 'सप्रभूता' शब्द का प्रयोग ही नही किया । प्रश्न यह है कि यदि 1688 ई की ऋति उचित थी तो उसे नियानित करने का निणय किसने और किस अधिकार से लिया था ? लॉक न स्पष्ट रूप से इसका कोई उत्तर नही दिया है। वह परोक्ष मे जनता (people) को ही सत्ता का सर्वाच्च अधिष्ठाता मानता है। हसान जपने ग्राथ 'सामाजिक अनुव व' (Social Contract) म इस प्रश्न के समाधान का मफल प्रयत्न किया है। वह अनुव ध द्वारा रचित राज्य की प्रभुमत्ता की सामाय इच्छा म अधिष्ठित कर देता है और इस प्रकार उसने लोकप्रिय प्रभुत्व (Popular Sover eignty) का समयन किया। रूसो के अनुसार अनुव व व्यक्तियों के दी पक्षा म हुआ है। एक पक्ष मे व्यक्ति अकेला है और दूसरे पक्ष मे व्यक्ति समाज के सदस्य के रूप में है। व्यक्ति के रूप म वह जिन अधिकारों का परित्याग करता है, समाज के सदस्य के रूप मे वह उह प्राप्त कर लेता है। रूसो के लोकप्रिय प्रभुत्व के सिद्धात ने प्राचीन निरकुशत तीय व्यवस्था को उलाड फेकने म महत्वपूण भूमिका निमायी थी। स्मरणीय है कि रूसो ना आदश प्रत्यक्ष प्रजातात्र या, न कि प्रतिनिधि प्रजातात्र । लेकिन उसने अनुपायिया के हाथों में अनजाने ही उसका सिद्धा त ब्यावहारिक एव प्रतिनिधि प्रजा त नात्मक सस्थाओं की स्थापना म सहायक हजा है।

18 वी सदी मे फास एव जमरिका मे कातिया हुई थी। रूसो की रचना Social Contract इन कातियों से पूर्व प्रकाशित हो चुकी थी। लाक के विचारों ने जहा अमेरिकी स्वत नता के युद्ध एवं सिवागन के निर्माण की प्रभावित किया था वहाँ रूसो का अपक्षाकृत कास की काति पर अधिक प्रमाव पढाथा। अमेरिकी कार्ति 13 उपनिवेशा के सविधानों में अनेक लोकता निक परिवतनों के लिए उत्तरदायी है। इन सभी सविधानों को एकतित करके फेच एवं अग्रेजी भाषा से 1781 ई में प्रकाशित किया गया था। इसने कास के नाति काल के सविधान निर्माण की प्रभावित किया। अमेरिकी स्वातात्र्य सम्राम का अपना इतिहास है। अमेरिकी उप निवेशो ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी जाधिक नीति के विरुद्ध विद्रोह किया था। अमेरिकी औपनिवेशिक जनता ने ब्रिटिश ससद म प्रतिनिधित्व की माग करते हुए और बिना प्रति निधित्व के कर न देन (No taxation without representation) की घाषणा की थी। ब्रिटिश शासन ने प्रतिनिधित्व की इस माग को स्वीकार नहीं किया। फलस्वरूप जपनिवेशा ने अपने को ब्रिटिश साम्राज्य से प्रथक करके नवीन राज्य-संयक्त राज्य अमेरिका-की नीव डाली और एक नवीन सर्विवान को 1787 ई म स्वीकार किया जो 1789 ई म लागू हुआ। स्ट्राग के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका का यह सर्वियान आधुनिक लिखित सविधानवाद का यथाय प्रारम्भ है। इस सविधान म 1776 ई की अमेरिकी स्वात य घोषणा के निद्धातों नो पूणरूपेण स्वीकार किया गया है तथा सर्वाच्न सत्ता भी इसम अधिष्ठित है। अमेरिकी सविधान में संघवाद की स्वीकार विया गया है जिससे विभिन्न समूहों को पूण स तृष्टि हो सके।

स्सो ता अमरीकिया वो अपक्षा फा जनता पर अधि एय प्रथ्यक्ष प्रभाव पडा है। यह फेंच भानितवारिया का अप्रदूत या। फेंच भाति वे प्रारम्भिक काल के नाति-वारिया पर उसका विगेष प्रभाव था। हमारे लिए इस भाति वो घटनाआ म सर्वाधिय महत्व वो घटना 1789 ई म स्टेट्स जनरत (National Assembly) द्वारा मनुष्या एव नागरिका व अधिकारा को घोषणा (Declaration of Rights of Man and Citizen) को स्वीभार करना है। 1791 ई म इसीसमा न फेच गणराज्य का सविधान स्वीकार किया जा अल्पकालिय सिद्ध हुआ। यह सविधान स्वोक्षय प्रभुत्व के गिद्धात पर आधारित वा और इसम अधिवारो का ममावा वा। स्ट्राग ने इसे आधुनिय लिखित सविधानवाद के विरास वी दिशा म द्वितीय महत्वपूण पर माना है। स्मरणीय है कि फेच माति ते राजनीतिक स्वता जता की जवा म स्वाध कर से प्रज्यवित्त कर दिया । 1791 ई का प्रथम फेच गणराज्य का सविधान अस्वाधी प्रमाणित हुआ लिक परवर्ती सभी फेच सविधान इस प्रथम सविधान के आधारभूत सिद्धात पर ही निर्मित हुए थे।

उन्नीसवीं सदी के उत्तराद्ध ने राष्ट्रीय सविधानवाद

19वी सदी म इटली एव जमनी म एकीकरण के आ दोलना के फलस्वरूप सविधानवाद को विशेष गति प्राप्त हुई थी और अनेक सविधानो का निर्माण हुआ था। सत्य तो यह है कि ब्रिटेन एव सयुक्त राज्य जमरिका के अतिरिक्त समी सविभान 19वी शताब्दी के उत्तराद्ध की ही उपज हैं। कुछ सविधान ता इस सदी के पूर्वाद्ध काल के भी है, लेक्नि उनम भी इतन आमूलचुल परिवतन हुए है कि इन्ह भी एक प्रकार से नय सविधान ही माना जायगा। इटली एव जमनी के एकी करण के आ दोलन 1870 ई के युद्ध के उपरात फास में गणतात्रीय सविधान की स्थापना के प्रेरणा स्रोत बन गये थे। 1848 ई क पश्चात इटली सात राज्यो म विभक्त था। इनम से सार्डीनिया का सविधान ही बाद म इटली के राज्य का सविधान बना ! 1859 70 ई के मध्य हान वाले अनेक विद्रोहा एवं युद्धों के फलस्वरूप इटली के अनेक राज्य सार्डीनिया म मिलते गये तथा इटली के वतमान राज्य का उदय हुआ । 1848 ई की फाति के बाद जमनी म पुवकालीन व्यवस्था का पुनर्जीवित किया गया। प्रशा के प्रधानमात्री विस्माक के नेतृत्व मे जमनी के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारम्म हुई। 1864 71 ई वे मध्य म तीन युद्ध लडे गये थे। इनक फलम्बरूप जमनी ने डेन-माक नी पराजित किया, जास्ट्रिया की जमन सब से पृथक कर दिया तथा फा स के द्वितीय साम्राज्य को भी पराजित किया था। फनस्वरूप पराजित राज्यों के स्थान पर नवीन सबैवानिक राज्या का उदय हुआ । डेनमाक म1864 ई में संसदीय प्रणाली की स्थापना हुइ । जास्ट्रिया एव हगरी म 1869 ई मे नवीन सविधान बना । 1871 ई में जमन संघ के स्थान पर जमन साम्राज्य की स्थापना हुई। इन सभी देशों के सविधानों मे त्रिटिश नमूने की ससदीय प्रणाली को अपनाया गया था। यह राष्ट्रीयता की सफलता के प्रमाण थे। इसी राष्ट्रीयता की मावना के कारण वाल्कन प्रदेश की विभिन्न जा

ने तुक शासन से मुक्ति पाने के लिए युद्ध का मार्ग जपनाया था। पिरनमी उदारवारी विचारधारा के प्रभाव एव सहयोग के फलस्वरूप 20वी मदी के प्रधम दशक में सव धानिक शासन का इस प्रदेश के अधिकाश देशों ने स्वीकार कियाथा। इन देशा मं 'एक राष्ट्र-जाति एव एक राज्य' वी मावना अत्यधिक प्रवल थी। 1912 ई एव 1913 ई के वाल्क युद्ध इसी राष्ट्रीयता के प्रतीक थे। उम्र राष्ट्रीयता ने इस प्रदेश में ही नहीं, विभिन्न साम्राज्यों के उपनियेशों मं भी स्वतंत्रता आ दोलनों का सूनपात किया था। 20वी सदी के प्रथम दशक थे भारतीय राष्ट्रीय जीवन में भी उग्रवादी एव मार्तिकारी आ दालनों का प्रारम्भ हुआ था। ये सभी स्वतंत्रता सन्नाम स्वतंत्र एव सवैधानिक शासन के लिए सच्च ये।

प्रथम विश्व युद्ध (1914 ई) की घटनाओं के परिणामस्वरूप सविधानवाद के प्रसार को और अधिक गति मिली थी। रूप के अतिरिक्त ज य सभी देशों में राजनीतिक सिवानों की स्वापना की गयों और प्राय सभी देशों में लोकत नारमक प्रणाली को अपनाया गया। परिस की शां ति सि धियों के परिणामस्वरूप फिललण्ड, एस्टोनिया, पौलैण्ड, चैकोस्लोवाविया आदि कई नवीन राज्यों का ज म हुआ एव प्ररयेक देश म लोक तनीय सिद्धा ता पर आधारित लिखित सविधानों की रचना हुई। प्रथम दिवस युद्ध के वाद राष्ट्रसध (League of Nations) की स्थापना स्ट्राम के शब्दों म सविधानवाद की दिशा में एक विशेष प्रमति थी। राष्ट्रसध वासाई (Versailles) एव अप सिंधयों का अभिन्न अग था। लेकिन राष्ट्रसथ आवहारिक रूप में एक सवधानिक प्रयोग था जो सम्भुत्व राज्या से सम्बध्धित विवादों को रोकन या खानितपूल बग ते निवदाने के विद्ध एक तराहनीय प्रयत्न था। अत राष्ट्रसथ की स्थापना उस समय तक के पश्चिमों प्ररोग के सवधानिक ग्रवास की दिशा में निश्चन के सवधानिक ग्रवास की दिशा में निश्चन की एक प्राति थी।

प्रथम एव द्वितीय विश्व युद्धों के मध्य सिवधानवाद को तीत्र अक्का भी लगा वा पहिल तो ऐसा लगा कि राष्ट्रीयता एव प्रतिनिधि लोकत न समुक्त रूप से मानव अधिकारा एव विधि के धासन की स्थापना के लिए सतत प्रयत्नशील हैं पर तु रूप में साम्यवादी घामन और इटली व जमनी में फासीवाद एव नाजीवाद के उदय ने लोक तान्तिन शासन एव सविधानवाद के विकास को भारा को अवक्द कर दिया र साम्यवादी एव पासीवादी शासना की स्थापना के फलस्वरूप सर्वाधिकारवाद (Totalia rianism) एव अधिनायकवाद (Dictatorship) भूत रूप हो उठे थे। जापान म सिनक अधिनायकवाद वी स्थापना हुई। फासीवाद एव नाजीवाद ने ससदीय व्यवस्था पर पातक महार किय और इटली व जमनी म उसना जात करने निरसुद्धा अध्यावारी शासन नी स्थापना नी तथा देश नी जनता ने उन मौतिक अधिकारा क उपनोग स्विच व र दिया जिनका व मासीवाद नी स्थापना के पून निर्वाध रूप न उपनोग करत रहे थे। 1939 ई म हिटलर ने अनेक देशा पर सुले रूप म आकृमण वर दिये थे। फरस्वरूप द्वितीय विदय युद्ध प्रारम्भ हुआ था।

द्वितीय विश्व युद्ध म जमनी एव इटली नी पराजय के बाद अनन देशों म

लोकत त्रीय सरकारा की स्थापना की गयी। जमनी की मित्रराष्ट्रा ने दो मागा म विभक्त कर दिया। पूर्वी जमनी के अतिरिक्त अय देदो—पालण्ड, हगरी, चंकोस्लीवाकिया, स्मानिया, बलारिया—म स्सी प्रमाव के अत्तवत सोवियत नमुन की जन-लोकत त्रीय (People Democracies) सरकारा की स्थापना की गयी थी। यह साम्यवादी अधिनायचाद या। यूगोस्लाविया भी साम्यवादी देदा है परत्तु वह सावियत प्रमुख के बाह्र है। अल्यानिया में भी साम्यवादी शासन है। इटली व जापान म सत्यदीय प्रणाली को अपनाया गया। 1949 ई म चीन म साम्यवाद की स्थापना हुई। एशिया के अधिनाय नेया है। इटली व जापान म सत्यदीय प्रणाली को अपनाया गया। 1949 ई म चीन म साम्यवाद की स्थापना हुई । एशिया के अधिकास नेयोदित राज्यो म पश्चिमी देप की सोहत नीय सरकारों की स्थापना हुई है। अस्तिका के नये स्वतात्र राज्यों म लोकतात्र की स्थापना हुई थी परत्तु वाद में कुछ देशा ने अधिनायकवादी लासनों को स्थीकार कर लिया है। साम्राज्यवाद को कुछ देशा ने अधिनायकवादी लासनों को स्थीकार कर लिया है। साम्राज्यवाद को कुछ रेक

सविधानवाद का लोकतन्त्र एव समाजवाद से सम्बन्ध

सविधानवाद का लोगतान एवं समाजवाद से सम्बन्ध ऐसा विषय हैं जिसका विदलेपण पुनरुक्ति-दोप के यावज़द भी वाछनीय हैं।

प्रारम्भ म सिव्यानवाद का स्वरूप क्षां प्राप्त हु।

प्रारम्भ म सिव्यानवाद का स्वरूप क्षांनीच्छ एव अप देगो म लोकता िनक
नहीं या। वूसरे शब्दो म, प्रारम्भ से ही सवैवानिक शासन लोकता िनक निश्चे । फेच
कारिकारिया ने स्वतन्त्रता की घोषणा (Declaration of Independence) एव
मानव अिकारो (Rights of Man) के अनुसार व्यक्ति की समानता के सिद्धात को
स वेह की देखि से देखा था। समुक्त राज्य अमेरिकी गणराज्य के प्रारम्भिक विचारको
में भी सामाण्य जनता के लिए जरसाह नहीं था। 19वीं सदी म इंगलज्य एवं अप देशा के विचारक लोकत न के प्रति सप्तेहरील थे। सभी स्नी पुरुषों को सावभीमिक
माताथिकार, राजनतिक जीवन में ध्योनका सहित सभी वर्षों को समान प्रतिनिधित्व,
जातीय एवं धार्मिक विभेद का अमाव लोकतान की पूणता के लक्षण है। कुछ देशों म
इस व्यावक रूप में लोकत न का आज वी अमाव है।

इस व्यापक रूप में लोगत न का आज की जमाव है। सिविधानवाद ने लोगत नीकारण की दिवा में सहायक 19वी सदी की महस्वपूण घटनाएँ निम्नवत है—जभेरिकी राष्ट्रपति जनसन का कायकाल, इगलण्ड का 1832 ई का सुवार विधेयक, 1848 ई की फ्रास की राज्यकाति एव अभेरिती गृह युद्ध। इन घटनाथा में से किसी ने भी प्रत्यक्षत लोकत न की स्थापना नहीं भी लेकिन लोकतान की अग्रसर करन में प्रत्येक न सराहनीय योग दिया है। जनसन के राष्ट्रपतितक काल में विशिष्ट लोगों के शासन की कहुं आलोचना की गयी। इगलण्ड के 1832 ई के सुवार विच एव परवर्ती सुपार विधेयकों ने समाव म विशिष्ट वर्गों के शासन म दरार डाल दी थी। 1848 ई की फ्रेंच धाति ने पूजीवादियों को चुनीती दी एव अनेक समाजवादी कार्यों ने फ्रास म पुन राजतान के समयक थान

वशियों के उदय को सम्मव बना दिया था। इस फ्रेंच श्रांति ने मटरनिख के

पश्चात जमन एकता ने लिए जमन जनता का प्रोत्साहित किया परानु उनना यह प्रयत्न असफल रहा । इटली म भी इसी प्रनार का जमफल प्रयत्न विया गया। मले ही ये स्वत त्र राष्ट्र एवता के सूत्र म आवड़ न हा सके ये परानु उनम आत्मित्रय की मावना जड पकड गयी थी। सयुक्त राज्य अमिरना क चारवर्षीय गृह युद्ध ने वासता वा समूलोच्छेदन कर दिया। राष्ट्रपति लिंकन ने इस गृह युद्ध-काल म ही उत्तेजक एव प्रेरणाप्रद छाड़ा में लोवता वा स्वाप्त के स्वता का समूलोच्छेदन कर दिया। राष्ट्रपति लिंकन ने इस गृह युद्ध-काल म ही उत्तेजक एव प्रेरणाप्रद छाड़ा में लोवता वा उद्योग वरते हुए वहा या कि लाक तत्र जनता का, जनता वे लिए, जनता हारा स्थापित शासन है और विस्व से इसना कमी विनाक्ष नहीं होगा।

इगलैण्ड म 1832 ई वे सुघार बिल के बाद 1867 व 1884 ई के तुपारों के द्वारा लोकत न ना अपसर विया गया था। 20वी सदी म स्त्रिया को भी मता धिकार प्रवान किया गया है। अमेरिका म थियोड़ोर रूजवल्ट, जुडरा विस्तर एव केकितल ही रूजवेल्ट के राष्ट्रपतिस्व-काल म लोकत नीकरण और अधिक गति प्राप्त हुई और आधिक शक्ति एव एकाधिकार पर लोकप्रिय नियन्त्रण स्थापित किया गया। मास मे तृतीय गणराज्य के अत्याद 1848 ई के शांतिकारिया के कायकम नो कमा किया विवा किया गया। जमनी म वीमर गणराज्य की स्थापना से लोकतन का कारम्म हुआ वा पर तु फासिस्ट शक्तिया के जवय ने लाकत न की प्रगति को एक बार पुन रोक दिया, किन्तु अमनी मे लोकत नीकरण दिगुणित बग से द्वितीय विस्व युद्ध के जपरा त गतिसील है। आज लोकत न एकमान स्वीकृत सबसेष्ट शासन है। अधिनायक्वारी भी इस सल्य को स्वीकार करने लये हैं। राजतान के दिन तो अब पूरी तरह लद चुके है।

समाजवाद एव लोकत प्रवाद

1848 ई की जाति ने समाजवाद का प्रश्न उपस्थित किया था एव समाज वाद श्रीमक वन ना प्रभावशाली नारा वन गया। 1848 ई मे प्रकाशित काल मार्स्स का साम्यवादी घोपणापत (Communist Manifesto) होयण से बचन के विए वन सचप का प्रतिपादन करता है। मान्सवादी हिसा व सघप को जाति के दौरान भ एव जाति वे बाद अनिवाय व आवस्यक मानते हैं। जाति के बाद स्थापित समाज में सवहारा वग का अविनायकत्व कायम होगा जो उनके अनुसार पूजीबादी तीर्क तन्ते से कि ही अधों मे अेप्ट है। इसने निपरीत, समाजवादियों का एक वग पूजीवादी समाज के विनाध एव पतन ने लिए जाति को आवस्यक नहीं मानता है। वे कमश और धीरे विकासवादी हम से लोक जीय पद्मित हारा समाजवाद की स्थापना करना चाहते है। ये विकासवादी या राज्य समाजवादी या लोकत जीय समाजवादी कहाते है। इमलण्ड के फीवयनवादी एव श्रम दस और जमनी के सावत हैं। वे अपिकास श्रमको ने हा प्रश्न के अपिकास श्रमको ने साम्यवाद एव उसके हिसात्मक रूप को अत्वीवतार किया है। युरोप के अपिकास श्रमको ने माम्यवाद एव उसके हिसात्मक रूप को अत्वीवतार किया है। युरोप के जियकास श्रमको ने माम्यवाद एव उसके हिसात्मक रूप को अत्वीवतार किया है। युरोप के जियकासवादी दक्षा मे बासविकता

के कारण नाति एव हिसा के प्रति उत्साह में कभी आयी है। 1936 ई में साम्यवाद के गढ सीवियतस्स में लिखित सविधान का निर्माण किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अनेक देशों में समाजवादिया ने अपने कायकम एव नीतियों की उपलिधयों के लिए सवैधानिक माग का अनुसरण प्रारम्म किया था। लेकिन समाजवाद एव सिविधानिवाद के समाजवाद एवं सिविधानिवाद के समाजवाद एवं सिविधानिवाद के समाजवाद एवं प्रवाद अपने के ये प्रयास असफल रहें थे और विमिन्न समस्याएँ उत्सन्त हुई थी। जमनी, इटली, स्वीडन, चैकोस्लोबाकिया, कास एवं अय येदों। में गम्मीर राजनीतिक सकट उत्पन्न हुए। 1920 ई के दशक मं विदिश स्विमक वत्त के सत्तालंड होने पर इरालैंग्ड में सविधान के प्रति स वेह उत्पन्न होने लगा था लेकिन वह शकामान प्रमाणित हुआ। इसी काल में न्यूजीलंग्ड एवं आस्ट्रेलिया में समाजवादी सत्तालंड हुए थे और उन्होंने सविधान के अधीन ही शासन चलाया था।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के प्रमुख देशा म लोकत त्रीय समाजवादी आ दौलनो के कारण सविधानशास्त्रिया के समक्ष अनेक समस्याएँ उत्पन हुई है। फास, इटली एव जमनी के नवीन सर्विधानों में ब्यवस्थित नियानण की अधिक आव-हयकता अनुभव की गयी है। 1946 ई के फ्रास के सविधान के अतगत जिसे मतदाताओं ने अस्वीकार किया था, ससदीय बहुमत के हाथों में अनियरित सत्ता को केदित कर दिया गया था। सोवियत क्षेत्र के जमन सविधान एव जमन साम्यवादिया के द्वारा प्रस्तावित सविधान के प्रारूप के बारे में भी यही कथन सत्य है। लेकिन जमनी के लोकत न समाजवादी (Social Democrats) एव फास के समाजवादी एक सीमा तक इस राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरोधी है। प्राय सभी नरमदलीय (Moderates) मौलिक अधिकारो एव नागरिको की स्वत नता की रक्षा को अधिका-धिक अनुमव करते है । ब्रिटेन ने श्रमिक दल के सत्तारूढ होने पर ब्रिटिश सर्विधानवाद का अत नहीं हुआ, जैसा कि कुछ आलोचका का विचार था। लोकतानिक समाज-वादियों की मा यता है कि विकासवादी एवं यायिक ढंग व सवधानिक लोकत न की पद्धति सं पूण समावयं करते हुए समाजवाद की स्थापना की जा सवती है। इस समावय के सादभ मे निश्चित रूप संअतिम निणय नहीं किया जा सकता परन्तू उपलब्ध प्रमाणो एव अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विभिन आर्थिक पद्धतियों से संवधानिक शासन का समावय सम्भव है। काल जे फेडरिक का मत है कि सविधानवाद समाज के सभी वर्गों के सातुलन पर आधारित होता है।

सभीक्षा की हिन्द से एक अय प्रश्न पर विचार करना महत्वपूण है। साम्य-वादी देशों में भी सर्विधाना की स्थापना की गयी है ? क्या इन साम्यवादी देशा को सबैधानिक राज्य की सना दी जा सकती है। सवधानिक राज्य के विकास का चित्रण उपरोक्त पृष्ठा में किया गया है। स्ट्रांग का मत है कि रूस ने सवप्रथम इसका उहलपन

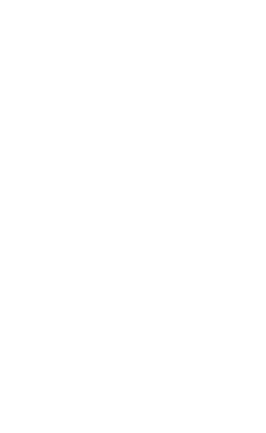
^{9 &}quot;Constitutionalism rests upon a balance of classes in society" — Carl J Frederich op est, p 35

किया है। 10 1917 ई म लाल काति हुई। इस काति की दो अवस्थाएँ था। प्रयम अवस्था माच की उदार काति थी । इसमें गणत त्रीय सविधान की स्थापना की गयी थी। फेच नमूने वे आधार पर ससद (Duma) एव मन्त्रिमण्डल का निर्माण निया गया। लेकिन नवस्वर 1917 ई म लेनिन के नतस्व म बोलरोविका न रूम को सोवियत गणत न घोषित कर दिया । यह न्नाति की द्वितीय अवस्था थी । 1918 ई मे लेनिन ने एक सविधान प्रस्तुत किया । स्ट्राग के अनुसार इस सविधान न पश्चिमी सविधानवाद मे दरार उत्पत्न कर दी। मानस वे सिद्धा ता पर नवीन राज्य का निर्माण किया गया । यह बहुमत पर आधारित सर्वधानिक शासन नही या अपितु सवहारा ना अधिनायकत्व था । लेनिन के हाथों म सवहारा का अधिनायकत्व साम्यवादी दल क अधिनायकत्व मे एव स्टालिन के हाथा म उसके व्यक्तिगत अधिनायकत्व म परिणत हो गया था । इस नवीन साम्यवादी राज्य म सम्पत्ति का सामूहिक स्वामित्व स्थापित कर दिया गया । सोवियत रूस के शासन म दो एस तत्व है जो उस सबधानिक राज्य से प्रथक करते है। प्रथम, एक ही राजनीतिक दल के प्राधा य के फलस्वरूप राजनीतिक दलीय अधिनायकरव की स्थापना एव द्वितीय, राज्य का सर्वाधिकारवादी स्वरूप। राज्य शासनतात्र द्वारा व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र---आर्थिक, सामाजिक एव धार्मिक — को नियमित एव निर्देशित करता है। इसम दो मत नहीं हैं कि रूस की शासन-पद्धति लोकताितक नहीं कही जा सक्ती । एकदलीय व्यवस्था ने लोकतात की हत्याकर दी है।

समीक्षा— उपरोक्त समीक्षा के स्ट्राम के अनुसार वो निष्कप है। 1 प्रवम, सबैधानिक राजनीवि को उसके इतिहास के सदम म ही समभा जा सकता है। एवं सबैधानिक राज्य के विकास में हर युप की अपनी देन है। उदाहरणाय, मूनारी सबिधानवाद ने राजनीतिक दशन की प्रेरणा एव राजनीतिक सगठन का स्वस्त प्रवन्ति किया है। रोमन सविधानवाद का प्रमुखतम अनुदेय विवि एव एकता का आदम प्रवन्ति किया है। रोमन सविधानवाद का प्रमुखतम अनुदेय विवि एव एकता का आदम है। मध्यपुणीन विकेदित साम तवादी समाज के विरुद्ध के द्वीकरण की प्रवित्त इगलाई, कास एव स्पेन के शासको की देन है। पुनर्जागरण-काल से के द्वीकरण की प्रवित्त की देन है। पुनर्जागरण-काल से के द्वीकरण की प्रवित्त की देन है। पुनर्जागरण-काल से के द्वीकरण की प्रवित्त की है। अमेरिकी एव फ्रेप नति सम्प्रम निवित्त सविधान रवान एव एवं एवं तिर तरता प्रवान की। अमेरिकी एव फ्रेप नति ने सम्प्रम निवित्त सविधान की साम स्वाप्त साम समम वय का प्रवात सिवान सहान किये और इस प्रकार स्वत त्रता एव सत्ता म सम वय का प्रवात किया। सपुक्त राज्य अमेरिका के सविधान ने सप्याद का जम दिया। 19वी सदी सुधार एवं राष्ट्रवाद का युग था। उसका प्रभाव सवधानिक राज्य पर स्वर्ध है। औषोगिक कोति के फलस्वरूप मध्यम वय को मताधिकार प्राप्त हुआ और आपुनिक तोकत के सन का निर्माण हुआ। और वोपोगक कानित ने राष्ट्रवाद एव सवधानिक सुधारों को और अपुनिक क्षात्र के फलस्वरूप प्रवार है। अपम विदय-युद्ध के फलस्वरूप अपुतार किया है। अपम विदय-युद्ध के फलस्वरूप अपुतार किया है। अपम विदय-युद्ध के फलस्वरूप अपुतार किया है। अपम विदय-युद्ध के फलस्वरूप अपुतार

¹⁰ Modern Political Constitutions p 47

¹¹ Ibid pp 53 55



शक्ति-पृथक्करण का सिद्धान्त THE THEORY OF THE SEPERATION OF POWERS

राज्य के प्रारम्मिक काल मे शासन के काय एव दायित्व बहुत कम थे। उस समय शासन का सम्ब ध केवल कर एकिनत करने तथा युद्ध एव सुरक्षा मान से था। विधि या नियमो का निर्माण या याय के सम्पादन का काय धार्मिक सस्याओ, परि वारा के प्रमुखो, साम तो या राजा द्वारा सम्पादित किया जाता था। प्राय यह समी काय प्रचलित रीति रिवाजो एव परम्पराओ ने अनुसार या निरकुश ढग से सम्पादित किये जाते थे। राज्या के विकास के साथ-साथ उनके कार्या में भी विद्धि हुई। शासन तान सुगठित होने लगा तथा उसके कायक्षेत्र की स्पष्ट सीमा निर्धारित की जाने लगी। आधुनिक राज्यों में शासन का काय मोटे रूप मं तीन वर्गा—विधायी, प्रशासकीय एवं यायिक—म विमाजित किया जाता है और इनका तीन पृथक अगो—व्यव स्यापिका, कायपालिका एव "यायपालिका — द्वारा सम्पादन होता है । शासन के यही तीन जग है। घासन के कार्यों के वर्गीकरण का प्रमुख आधार कार्यों की प्रकृति की सिद्धात है। एक से काय एक वस में रखे जाते हैं। राज्य की इच्छा आदेशा ए^व विधिया व माध्यम स अभिव्यक्त होती है। अत राज्य की इच्छा को व्यवस्थित करके श्रावद्याएव विधियाके रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यही विधि निर्माण है। इन विभिन्ना को नियायित करने के लिए प्रशासकीय अभिनसीओ की आवस्यकता होती है । फलस्वरूप कायपालिका की स्थापना की गयी । "यायपालिका द्वारा विधियाँ फी व्यवस्था एव विधिया के क्रिया विधन सम्बाधी विवादों का निषय किया जाता है। विधि निर्माता एव प्रशासक के काय एक दूसरे सं मिन हैं[®]। इसी प्रकार, प्रशासक एवं यायाधीश के नाय म अंतर है। एक मत यह है कि शासन के इन तीना अगी मो एक दूसर स स्वतः व होना चाहिए तथा पृथक पृथक व्यक्तियो द्वारा प्रत्येक अग व नायों ना सम्मादित किया जाना चाहिए। उहे एक दूसरे के कार्यों महस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस ही शक्ति-पृथकरण का सिद्धान्त कहत हैं। गेटेल के अनुसार 'यह सिद्धान्त नि (ग्रामन न) नायौँ को पृथक पृथक व्यक्तिया द्वारा सम्पाटित निया जाम और प्रत्यक विमाग ना अपने क्षेत्र न कार्यों स ही सम्बाध हा तया एक दूसर क

क्षत्र म बाद हस्तक्षप प कर एवं अपन क्षेत्र म स्वतं व हो, वस्ति-गुपातरण ना मिद्रा त पहलावा है। ^{प्र}

राज्य र नायाँ ना तीन मामा म वर्गीनरण सायमीमिश रूप म माप नहीं है। एक मत यह है कि शामन की शक्तिया का प्रम्याप (1) राज्य की इच्छा के निमाण एवं अभिव्यक्ति तथा (n) व्यक्त इच्छा क त्रिया वयन न हाता है। प्रथम बा मध्याप मुविधान एवं माधारण विधि र निमाण म है और दितीय जा सम्बाध इन विधिया का जियायित करने गाहै। इस होन्ड सा वाय वा सम्पादन रायपालिका धिस्त का हो एक भाग है। अत रायपालिया धस्ति वे निम्न काव हाउ चाहिए

(1) व्यापन अर्थ म नायपालिका न नाय हैं निरीक्षण, निर्देशन एवं नियानण। (2) प्रशानकीय काय अयात् पासन क कायपालिका सम्बंधी कार्यो का

सम्पादन ।

(3) पायिक भाग ज्ञात विधि को व्यान्या एवं वयक्तिक मामला म विधि का त्रिया वदन ।

क्य लेखक पाविक शक्ति का सामायत रायपालिका शक्ति का एक अग मानत है। अत प्रांस म शक्ति-पृथववरण व सिद्धात वा इयसण्ड एव समूक्त राज्य अमरिया स निम्न महत्व है।

कुछ विचारक यह मानत हैं कि व्यवस्थापिका, नायपालिका एव 'यायपालिका क वर्गीकरण म दासन की सभी दास्तिया का उल्लेख नहीं हाता है। प्रो डीले (Dealey) के अनुसार शासन की शक्तियाँ पांच भाषा म वर्गीकृत होनी चाहिए (1) विचारात्मर (Deliberative), (2) विधायी (Legislative), (3) काय-पालक (Executive), (4) प्रशासकीय (Administrative), एव (5) चायिक (Judicial) 1

प्रो विलोधी (Prof Willoughby) न मतदाता-वन (electorate) को धामन के प्रयक्ष अंग के रूप म भा यता दी है। उनका मत है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जस देशा म जहाँ लावत त्र विकसित रूप म है तथा जिन देशा म सावजनिक नीति के निर्धारण म उपत्रम (initiative) एव जनमत सग्रह (referendum) महत्वपूण भूमिका निमात है, मतदाताओं का शासनत त्र के एक अनिवाय जग या एक प्रयक्त शाखा के रूप म स्वीनार करना चाहिए। विलोबी प्रशासकीय शक्ति को कावपालिका से प्रथक मानता है। प्रथम या काय बेचल कायपालिका के जादशा को कियाचित करना होता है जब वि कायपालिका को निणय लेन के साथ साथ नीति निर्धारित करनी पडती है और सामाय निरीक्षण, निर्देशन एव नियात्रण सम्बाधी काय भी सम्पादित करने पडत हैं।

¹ Gettell Political Science, 1956, p 209
2 Dealey The Development of State pp 144-145
3 Willoughby, quoted by H N Sinha Outlines of Political Science,

p 131

लेकिन विलाबी के विचार आमर है। मतदाताजा को शासन का पृथक जग नहीं माना जा सकता क्यांकि इनसे राजनीतिक एउ विधिक सप्रमुता का अन्तर ममाख हो जायेगा। मतदाता राजनीतिक प्रमुहं और वह सासन या विथिक सप्रमुका निर्माता है। कुछ विश्वेष परिस्थितियाँ में यह सम्भव है कि मतदाता सीधे उपनम या जनमत सम्रह के माध्यम से अपनी राय व्यक्त तर द लेकिन व शासन के अग के रूप म राज्य की नीतियां का निर्माण एवं प्रशासन उहीं कर मस्ते। द्वितीय, प्रशासकीय एव कायपालिका सम्बाबी कार्यों म भेद उचित एवं तकसगत माना जा सकता है लेकिन दोना को शासन की दो पृथक शासाएँ स्वीकारन का अब तक का दुरुपगेग है। प्रत्येक सरकार म प्रशासकीय एव कायपालिका सम्बाबी काय एक ही अग को सौपे जाते है। इनको पृथक करन स कार्यों म दुगणन (duplication) एव अतित्रमण (overlap) की सम्मावना उत्पन हो जायेगी। अत शासन की शक्तिया के परम्परा गत वर्गीकरण-व्यवस्थापिका, कायपालिका एव यायपालिका-को मानना ही थेयष्कर है।

शक्ति-पृथक्करण के सिद्धान्त का विकास

शासन के कार्यों को तीन वर्गों में अत्यात प्राचीन काल से ही विभक्त किया जा रहा है। अरस्तू ने कार्यों के जाघार पर शासन को तीन जंगा म विमक्त किया या-सावजनिक सभा, दण्डाधीक्ष एव यायपालिका । इन तीनो जगा के कार्यों को उसने नमश विचारात्मक (deliberative), वण्डाधीश सम्ब बी (magisterial) और यायिक (judicial) की सना दी थी । लेकिन एथे स के नगर राज्य म शक्तिया का पृथकरण नहीं था। सावजनिक सभा (Ecctessia) विधायी कतव्या के अतिरिक्त कायपालक एवं यायिक कार्या को भी सम्पादित करती थी । रोमन विचारक पोलिबियस एवं सिसेरो की रचनाओ म भी इसी प्रकार के विचार प्रतिपादित किय गये हैं। इत विचारका ने रोमन गणराज्य की सफलता का रहस्य उसके सगठन म ब्याप्त अवरोध एवं संतुलन की व्यवस्था की माना है। पालिवियस ने 'रोम का इतिहास' (छट्वा अघ्याय) नामक अपनी रचना से सीनेट (Senate), काउसिल (Consuls) एवं ट्रिपूर (Tribunes) म शासन शक्ति को स तुलित रूप में विभाजित करने का उल्लेख किया है। लेकिन व्यवहार म रोमन सीनेट सर्घोच्च यी और शासन के अप जग उसके अधीन थे। रोमन साम्राज्य एव साम ती मध्य युग म शक्तियों के पृथवकरण का जैत हो गया था। 14वी सदी में पेडुजा निवासी मार्सोलियो (Marsilio of Padua) की रचनाओं म यह धारणा पुनजीवित हुई। मार्सीलिया ने झासन के विधायी एवं कायपालिका सम्ब बी कार्यों में स्पष्ट विमाजन किया है। ⁵ 16वीं सदी म फ्रांसीसी विचारक जी बोदा (Jean Bodin) वन याय सम्बन्धी कार्या को स्वत न अधिकारिया

⁴ Politics Bl. IV, Chap XIV
5 Marsilio of Padua In the Defensor Paeis (1324)
6 De la republique, Bk I Chap X

को सापने पर वल दिया। बोदा ने राजा द्वारा न्याधिक कतव्यो को सम्पादित करन से उत्पन्न होने वाले खतरा की विस्तृत चर्चा की है। 17वी शताब्दी में इमलैण्ड में प्यूरि-टन जाति के फलस्वरूप विस्ति पुषकरूपण पर विद्याय वल दिया गया और विधायी एव कायपालिका के कार्या के भेद को स्पष्ट इस्प से व्यक्त किया गया। जान ताक ने शासन की शक्तियों को तीन जाग में विभक्त किया है—विधायी, कायपालिका एव फेडरेटिव (Federative)। फेडरेटिव बग से लॉक का तास्पय राज्य के राजनयिक अभिकरणो (diplomatic agencies) से हैं। प्र

राजनीति शास्त्र में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धात के महत्व म वृद्धि राज-गीतिक स्वत तता के महत्व के साथ-साथ हुई है। 17वीं शताब्दी में यह सिद्धात गिश्चित रूप धारण करने लगा था और 18वीं सदी में यह राजनीति शास्त्र म चर्ची का मुख्य विषय वन गया था।

फेच विचारक भोटेस्बयू न सबप्रथम शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त की अपनी रचना Spirit of the Laws (1848) में अधिकृत व्यारया की है वह इसे राजनीति शास्त्र का आधारश्रत सिद्धा त बताता है।

मोटेस्क्य के द्वारा शक्तियों के प्रथक्करण के सिद्धात का विकास विशेष ऐतिहासिक वार्तावरण म हुआ था। मी टेस्क्यू के समय मे फास म निरकुश राजतात्र का बोलवाला था। शासन की शक्तियों का प्रयोग वशानुगत राजाओ एवं पार्नियामेण्टा के द्वारा किया जाता था। फा सीसी पालियामेण्ट या ससद जन प्रतिनिधि सभाएँ नही थी। इगलैण्ड की ससद की माति उन्हें विधि निर्माण की शक्ति भी प्राप्त न थी और न उनका कायपालिका व राष्ट्रीय धन पर नियानण ही था। वे प्रमुख रूप मे याया-लय ये तथा उन्ह कुछेक प्रशासनिक मामलो को नियम्त्रित करने की शक्ति प्राप्त थी। मि त्राण फ्रेच पालियामेण्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं हाते थे। इनके सदस्य अधिकाश-तया यायाबीश, नोटेरी (Notaries) एव अ य अधिकारी हुआ करते थे जी अपने पद कय करके प्राप्त करते थे । इनका जनता के निवासित प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता था। इनके हित भी सामा य हिता से सम्बंधित नहीं ये क्योंकि यह सभी मदस्य समाज के उच्च वग से ही सम्बन्धित हुआ करते थे। शासन मे उनका प्रभाव भी विशेष नहीं था। अत तत्कालीन फास में शासन की सम्प्रण क्षक्तिया राजा के हाथा मे केदित भी और वह अपनी इच्छानुसार ही विधिया के निर्माण के साथ-साथ शासन और न्याय नरता था। फलस्वरूप का स में निरकूश व्यवस्था प्रचलित थी और नागरिक स्वतात्रता का पूण अभाव था। मा टस्क्यू व्यक्ति की स्वतात्रता का प्रवल समधक था। अपनी रचना म वह इसी प्रश्न पर मनन करता है। उसन व्यक्ति की स्वत नता के हेतु निरकुश सत्ता को सीमित करने की आवश्यकता का अनुमव किया था।

⁷ Two Treatises of Government, Chap XII
8 Montesquieu L' Esprit des Lors (The Spirit of the Laws), Bk XI
Ch IV

मो टेस्क्यू की हप्टि म स्वतात्रता श्रेष्ठ मानवीय गुण ह । शक्ति पृयनकरण क सिद्धान्त का समभने के लिए यह आवश्यक है कि यह भी गात कर लिया जाय कि मो टस्क्यू की दृष्टि म राजनीतिक स्वत नता (Political Liberty) स क्या अब हैं। मो टेस्क्यू के अनुसार स्वत कता विधि सम्मत जाचरण है । 'स्वत कता विधि-सम्मत कार्यों को करने का अधिकार है। यदि काइ नागरिक विधि द्वारा निषिद्ध कार्यों की करता है तो वह स्वतात्र नहीं है क्यांकि इससे उसके आय साथिया को भी समान शक्ति प्राप्त हो जायगी। " इसका अय है कि सभी नागरिका की विधि द्वारा निर्धारित सीमा वें औचित्य को स्वीकार करना चाहिए। मो टस्वयु के लिए विधि से तात्पय निस्ति या अलिखित कानून या परम्परागत विधिया एव परम्पराओ स ही नही था । उसके अनुसार विधि एक सिद्धा त है अयात एक विशेष प्रकार के शासन का सिद्धान्त है। इसे हम वाधित (desirable) सम्यता की भावना की भी सज़ा दे सकत हैं। स्मरणीय है कि विधि, परम्परा, अलिखित कानून, यहाँ तक कि शासन के स्वरूप का निर्घारण भी भावना द्वारा ही होता है। शासन के किसी विशेष सगठन के फलस्वरूप शासन म मनुष्या को स्वत नता प्राप्त नहीं हो सकती । लोकतन्त्रीय एव कुलीनत त्रीय व्यवस्थाए अपने आप म स्वतन्त्र नही होती। ता प्रधन यह है कि स्वतात्रता फिर कहाँ सम्भव है ? मो टेस्क्यू के अनुसार राजनीतिक स्वत नता मध्यम (moderate) सरकारा मही सम्मव है लेकिन हमेशा इनमे भी स्वत बता सम्भव नही होती। राजनीतिक स्वत वता तमी सम्मव हाती है जब कि उनमे धक्ति का दुरपयोग नहीं होता। मोटेस्क्यू का कथन या कि यह अनुभव सिद्ध है कि 'प्रत्येक सत्ताधारी व्यक्ति ने उस हद तक सत्ता का दुरपयोग किया है जब तक कि उस पर प्रतिबंध निर्धारित नहीं किये जाते हैं। इस बुराई का दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि सत्ता द्वारा सत्ता (power) पर उचित दग से प्रतिब ध लगाकर सत्ता के दुरुपयोग को रोका जाय।

मोटेस्नयू इसको सम्मन मानता था। उसके अनुसार सिवधान ऐसा हाना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को विवि के विपरीत काय करने एवं विधि-सम्मत कार्य करने के लिए बाध्य न हाना पड़े। मोटेस्बयू का इसमें यह तान्यय था कि व्यक्तियों के एसे तिकायों की स्थानना की जाय जो एक दूसरे के समकक्ष हो। यदि कार्य तिकाय अपन क्षेत्र का अतिकमण करना है तो दूसरे निकाय के द्वारा उसका प्रतिवाद होना चाहिए। प्रयोक निकाय (body) को कुछ शक्तिया प्राप्त होनी चाहिए जिसकी वे स्वय अतिकमण से रक्षा करे। प्रतिस्पर्यी अधिकारियों म बाक्ति का विमाजन इस प्रणाली की विरोधता है।

मी टेस्क्यू की यह धारणा थी कि इस व्यवस्था के फलस्वरूप इमलण्ड मे

^{9 &#}x27;Liberty is a right of doing whatever the laws permit and if a citizen could do what they forbid, he would be no longer possessed of liberty, because all his fellow citizens would have the same power.' — Montesqueu

व्याप्त राजनीतिक स्वतन्त्रता को प्राप्त किया जा सकता है। राजनीतिक स्वत त्रता मन की ऐसी निश्चिन्तता की स्थिति है जो प्रत्येक व्यक्ति म सुरक्षा की मानना पर आधारित होती है। इस स्थिति के लिए यह आवस्थक है कि शासन ऐसा हा कि किसी को किसी से मयमीत न होना पढ़े। मोटेस्बयू के शब्दों म स्वत त्रता सुरक्षा में या सुरक्षा सम्बय्धी जन भावना में निहित है। 10 जब प्रजा को जपनी निर्दोपिता के रक्षाथ सरक्षण प्राप्त नहीं होता तो स्वत त्रता समाप्त हो जाती है।

मो टेस्क्यू अन्य उदारवादी विचारको की माति यह स्वीकार करता था कि राज्य के द्वारा व्यक्ति की स्वत नता का अविजन्मण किया जाता है। अत उसने स्वतन्तता को राज्य के नियानण से मुक्त करने का आदश्च अपने समक्ष रखा था। मो टेस्क्यू तत्कालीन फान्स की निरक्ष्य राज्य नीय व्यवस्था को राजनीतिक स्थत नता का घर्मू मानता था। वह उसे सोमित करने के साधनो की खोज मे था जिससे कि निरक्षुश्चत जीय व्यवस्था पर जवरोध लगाकर उसे साधनो की खोज मे था जिससे कि निरक्षुश्चत जीय व्यवस्था पर जवरोध लगाकर उसे साधनो की दोज मे या जिससे कि निरक्षुश्चत जीय व्यवस्था पर जवरोध लगाकर उसे साधनों के स्वत् अवस्था का प्रतित हुई। अत उसके इस सस्या का समक्षण किया।

मो टेस्क्यू ने इगलण्ड की भी याना की थी और उसने वहा की शासन प्रणाली का निकट से अस्ययन भी किया था। उसके अनुसार इगलण्ड मे पायी जान वाली राजनीतिक स्वत नता का रहस्य यह तथ्य था कि शासन की श्रास्तिया एक व्यक्तिया या व्यक्तिन्मपूर्व मे केंद्रित न होकर प्रथक प्रथक व्यक्तियों के हाथा म थी। उसने इस स्वयस्था से प्रेरणा महण करते हुए शक्तियों के पृथकरण के सिद्धात का प्रतिपादन किया था।

मा देश्यू के अनुतार प्रत्यक शासन में तीन प्रकार की सिन्तया होती हैं।
य हैं नगरा विधायी शक्ति, कायपालक शिवत जो अतरांष्ट्रीय विधि सम्बधी मानला
से सम्बधित होती हैं तथा वह कायपालक शिवत जो देश की विधि सम्बधी मानला
से सम्बधित होती है। प्रथम शक्ति के अत्यात राजा या शासक स्थायी एव अस्यायी
विधिया का निर्माण करता है तथा पुरानी विधिया को संशोधित या रद्द करता हैं।
कायपालक शिवत के अत्यात युद्ध या सिंध के अलावा राजदूता की दूसरे देशों में
निमुन्ति और दूसरे देशा के राजदूता का स्वायत किया जाता है तथा सावजनिक
सुरक्षा की स्थापना एव देश की आक्रमणों से रक्षा की जाती है। मूनीय के अत्यात
शासन अपराधियों को दिख्त करता है तथा व्यक्तियों के मध्य उत्यन विवादा का
निवटारा करता है।

जब विषायी एव कायपालिका र्जान्तया एक ही व्यक्ति या शासका के एक ही निकाय में केटिंदत हो जाती है तो स्वत पता का अस्तित्व नहीं रहता क्यांकि ऐसी

^{10 &}quot;It (political liberty) consists in security, or in the opinion people have of this security "—Montesquieu L Esprit des Lois, Bl. XII, Ch. III

अवस्था भ इस बात ना मय हो जाता है नि कही राजा व सीनेट अखाचारी विधिया का निर्माण करके उन्हें अत्यानारपुण ढम स क्रियाचित न करने लगे ।

"द्वी प्रकार यदि यायिन सक्ति को विधायी या कायपालिना सक्ति ते पृषक नहीं किया जाता तो स्वत त्रता की स्थापना नहीं हा सकती । यदि इस (याविक सिन्त) का विधायो सक्ति ने साथ सयुक्त कर दिया जाय तो प्रजा क जीवन व स्वत त्रता को स्वेच्छानारी नियत्रण का दिखार होना पढ़ेना क्यांकि एकी स्थिति में यायाधीश ही विधि निमाता होगा । यदि यायिक शक्ति का कायपालिका सिन्त के साथ सयुक्त कर दिया जाय तो यायाधीश का व्यवहार हिसायुक्त एव अध्याया पूण हो ककता है। यदि एक ही व्यक्ति या व्यक्तिया के ममूह म बाह व जिनजाल वा या साधारण जनता म से ही क्या न हा, तीना दिक्त्या वर्णात विधि निर्माण, सावजनिक प्रस्तावों का त्रिया व्यवन एव व्यक्तियों के विवादा को तय करते के कार्य केंद्रित कर दिये जायें तो प्रयोग चीज का अन्त निर्दिश्त है। "11

प्रतिद्ध विधिवेता क्षेत्रस्टोन ने भी द्यक्तियों के पूर्वकरण का समयन किया है। उसके अनुसार 'जब कभी विधि निमाण एव निया वयन के अधिकार एक व्यक्ति या एक ही व्यक्ति समूह को प्राप्त होत हैं तो सावजनिक स्वता तता नहीं हो सकती। या एक ही व्यक्ति समूह को प्राप्त होत हैं तो सावजनिक स्वता तता नहीं हो सकती। या सकता है एव उन्हें अस्पा चारी करा से निया वित्त भी किया जा सकता है क्यांकि उसके पास वे सब शक्तियों होती है जो विधि निर्माता के रूप में उसे प्राप्त होती चाहिए। यदि "याधिक स्विधि विभाग शक्ति म समुक्त हो तो प्राप्त का जीवन, सम्पत्ति एव सुरक्षा ऐसे स्वैच्दा चारी यायाधीयों के हाथ में होगी जिनके निषय उनके विचारों द्वारा ही निर्देशित होगे, न कि किसी मीलिक विधि विद्वात द्वारा जिनका पासन यासाधीयों द्वारा किया जाना जिनवाद हो। यदि याधिक शक्ति का सम्पत्तिका से सहस्त हो तो इस पत्ति के स्वराप्त के स्वयस्थापिक। से कहां अधिक शायनात्मित हो से में स्वराप्त हो विद्वात हो । यदि याधिक शक्ति शायनातिका से सहस्त हो तो इस एका के स्वराप्त के स्वराप्त हो सो स्वराप्त हो विद्वात हो से स्वराप्त हो से इस्त विद्वात हो से स्वराप्त हो से इस्त विद्वात हो से स्वराप्त हो से इस पत्ता है हो है ।

मार्-देश्यू के इस सिद्धांत का उन समाजा पर विशेष प्रमाव पढा जो शरण चारी शासनो से पीडित । 18वी शताब्दी के लेखका पर इस सिद्धांत का विशेष प्रमाव था तथा परिवर्ती सदियों के राजनीतिक चित्तन एवं ब्यावहारिक राजनीति दीनां ना इस सिद्धांत ने प्रमावित किया है। अमेरिका एवं फास की क्रांतियों की इस सिद्धांत से विशेष प्ररेणा प्रास्त हुई थी।

आलोचना---इस सिद्धा त नी अनक आधारो पर निम्न आलोचना की गर्मी है (1) मोटेस्क्यू को इस सिद्धात के सम्बंध में घेट ब्रिटेन स प्रेरणा मिली थी। उसनी वारणा थी कि ग्रेट ब्रिटेन में व्यक्तियों को जो स्वत नता प्राप्त है उसका कारण

L Esprit des Lois, Bk XI, Ch VI
 Blackstone Commentaries on the Laws of England, Vol I, pp 146 and 269

वहीं वे शानन म शक्तिया का पृथक्त रण है परानु यह मा टेस्त्यू का श्रम था। इगलण्ड म उस समय समरीय प्रणाली का प्रारम्म ही हुआ था तथा दलीय व्यवस्था का भी वतमान रूप पूरी तरह उत्तर कर सामने नहीं आया था। उस समय इगलण्ड म राजा और समद के दाना सदना की धिक्तिया म सातुलन था तथा यायपालिका पर्याप्तत स्वताय थी। सम्दर ह कि मो टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित धिक्त-पृथक्तरण का आधार ही गतल था।

- (2) यह सचन भी सत्य नहीं है नि शिंकत पृथकरण के विना स्वत नता की रक्षा सम्मव नहीं है। ससदीय धासन-प्रणालिया म श्रिकत पृथकरण नहीं हाता लेकिन यह कहना गलत है नि बढ़ी स्वत प्रता नहीं है।
- (3) गामन के कायों म सावयवी एनता होती है। उन्ह पूणरूपण पृथक करने का अप सासन-ध्यवस्था का पगु बना देना है। अत इस सिद्धात की भी सीमाएँ हैं। इसे सावभीमिक रूप से लागू नहीं निया जा सकता है। ऐसा करना अविवेकी एव अध्यावहारिक होगा। शक्तिया के पृथककरण का अप है कि सासन के विधायी, कायपालक एव यायिक काय शासन के विभिन्न विभागा द्वारा पृथक-पृथक रूप से सम्पादित किये जायें। इसका अय निरंपक्ष पृथकता नहीं है। शासन के विभिन्न अग जब एक दूसरे के साथ मिलकर काय करते ह तभी उनके द्वारा वादित लक्ष्य की प्राप्ति सम्बव है।
 - (4) अनक निद्वान शासन के कार्यों को विधायी, कायपालक एव यायिक कार्यों म वर्षीकृत करना स्वीकार नहीं करते। वे मो टेस्क्यू के शक्ति पृथवकरण के सिद्धात को स्वीकार नहीं करते।
 - (5) शिक्तयां के पृथक्करण का एक स्वामाविक परिणाम यह होता है कि धासन के सभी अथा का समान महत्व है। लेकिन यह सत्य नहीं है। व्यवस्थापिका का सामन महत्व है। लेकिन यह सत्य नहीं है। व्यवस्थापिका का सामनिधित्व का सामन के दो अप अगा से अधिक महत्र ह। व्यवस्थापिका जनता का प्रतिनिधित्व कारती है और जनता की इच्छा का विधिया के एय म अभिव्यक्त करती है। सोय दोना विभाग विधान मण्डल द्वारा निर्मित विधिया को सुवार रूप मिना विधान के स्ववस्थापिका से पृथक हो हो हो सिवा सही अर्था म नियाविका से पृथक हो के फलस्वरूप यह सम्भव है कि विधिया सही अर्था म नियावित न की जायें।
 - (6) लोकता न में शक्तिकों के पूचकरण की कीई आवश्यकता नहीं है और न उसकी कोई व्यावहारिक उपयोगिता ही हं। माटेंस्क्यू ने फांस की तत्कालीन निरकुशत तीय व्यवस्था के प्रभाव में शक्तिया की पूथकता का सुभाव दिया था। लोकतान मंतो शासन की शक्ति जनता के प्रतिनिधिया के हाथ में होती ही है अत अत्याचार की सम्मावना कम होती है।

सपुक्त राज्य अमेरिका एव शक्तियो का प्रथक्करण

फाइनर के अनुसार "यह कभी चात नहीं होगा कि अमेरिकी सविधान निमा-ताजा ने मोटेस्क्यू के सिद्धात से अथवा स्वताजता और सम्पत्ति की रक्षा की माग स प्रेरित होकर शक्ति पृथक्करण कसिद्धात का अमरिती सविधान म स्यान दिया है। लेकिन यह स्पष्ट है कि व मा टेस्वयू द्वारा व्यक्त एव पारिमापित राजनीतिर स्वत प्रना को प्राप्त करना चाहते थ तथा निरनुशतन्य को सीमित करन के दब्दार था इसन स्पष्ट है कि वे मो टेस्नयू के सिद्धान्त स प्रमावित थे। अमरिकी सविधान निमानाजा ने जानवूभकर विस्तृत रूप स शक्ति पृथवररण वे सिद्धाःत ना अपनामा है।""

वर्तमान युग में संयुक्त राज्य जमेरिका ही शक्ति प्रवनरण के सिद्धान्त की

स्वीकार करने वाला सबसे महत्वपुण देश है।

मसेच्यूसेट्स राज्य के सविधान (1780) म इक्ति-मधक्करण के सिद्धात की द्याप स्पष्ट है। इस सविधान म घोषणा वी गयी है कि "इस राज्य म व्यवस्थापिका कभी भी न तो कायपालक एव यायिक शक्तिया का प्रयोग करगी और न ही यायपालिश विवायी एवं कायपालिका शक्ति का या उनम से विसी एक का प्रयोग करगी, जिसस शासन ध्यक्तिया की स्वेच्छा पर निमर न होकर विधि पर आधारित हा ।" सात वप पश्चात 1787 ई में सयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय सविधान का निमाण करने वाले सम्मेलन के सदस्या पर इस सिद्धान्त का प्रमाव स्पष्ट या लेकिन उनके द्वारा इस सिद्धात को कछ संशोधित रूप म ही मायता दी गयी है।

हैमिल्टन, मेडिसन एव जय (जो सभी वाद म सयुक्त राज्य अमरिका के राष्ट्र पति वन) ने 'फडरलिस्ट' नामक रचना में कहा है कि "एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियो के हाथों म विधायी, कायपालक एव यायिक शक्ति के एकीकरण को ही अत्याचार त न की सन्ना दी जानी चाहिए, मले ही वह व्यक्ति एव व्यक्ति-समूह वशानुगत जाधार पर नियुक्त हा या मनानीत हो या जनता द्वारा निर्वाचित हो ।" जेम्स मेडीसन में ने 'फडरलिस्ट में ही अपने मत की पुष्टि म मो टेस्क्यू से उद्धरण प्रस्तुत किये हैं। एक दूसर सदस्य जॉन आदम का कथन था कि "यदि एक ही प्रतिनिधि समा को सभी शक्तिया-विधायी कायपालक एव यायिक-दे दी जाती है तो ऐसी व्यवस्था निर्दुर्ग शासन से भी अधिक है और देरअवेर में अल्पसब्यका के अधिकार का अतिक्रमण होगा। '

केलीफोर्निया राज्य के सविधान म घोषणा की गयी थी कि शासन की शक्तिया तीन विमागी-विधानमण्डल, कायपालिका एव यायपालिका-म विमाजित हो^{गी} और कोई व्यक्ति जिसे इनमें से एक भी शक्ति के प्रयोग का अधिकार प्राप्त नहीं होगा किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा।

सयुवत राज्य अमरिका का वतमान सविवान भी शक्ति पृथवकरण पर आधा रित है। विधायी शन्ति कार्येस में, 15 कायपालिका शक्ति राष्ट्रपति में 10 और यायिक

¹³ Finer H The Theory and Practice of Modern Government, 1956,

Madison The Federalist, Essay XLVII

Article I 16 Article II

राक्ति सर्वोच्च यायालय तथा अय सधीय यायालया मे, जो समय समय पर काग्नेस द्वारा स्थापित किये जायँ, अधिष्ठित है। 12 यद्यपि सविधान में शक्ति पृथकरण का काई स्पट्ट उत्लेख नहीं है पर तु शासन के तीना अगा को पृथक पृषक अनुच्छेदा के द्वारा पृथक शक्ति प्रदान की गयी है। इस व्यवस्था से अमेरिकी सविधान में शाक्तिया के पृथकरण को स्थापना हुई है। अधिकाश अमेरिकी नागरिक शक्तियों के पृथकरण को प्राष्ट्रिक विधि की माति विवाद के परे मानते थे। अमेरिकी सर्वाच्च यायालय ने मी अमेरिकी सर्वाच्च में शक्ति प्रवाद के मी अमेरिकी सर्वाच्च सर्वाच्च के अमेरिकी सर्वाच्च सर्वाच्च के अमेरिकी सर्वाच्च सर्वाच्च के अमेरिकी सर्वाच्च सर्वाच्च के अमेरिकी सर्वाच्च है। सर्वोच्च यायालय के अनुसार अमेरिकी सर्वाच्च है। सर्वोच्च यायालय के अनुसार अमेरिकी सर्वाच्च है। सर्वोच्च यायालय के अनुसार अमेरिकी सर्वाच्च को गयी है वे तीन—कायपालक, विधायी एव आयपालिका—विधायों के मच्य विभाजित हैं। इस प्राण्वों के सच्च नम्पादन के लिए यह आवस्यक है कि जिन व्यक्तिया जो एक साखा की शविवाय प्रदान की गयी है। उन्हें सुचरे विभाग को प्रदत्त विभागी में इस्त-

सीमित होना चाहिए। 18 अमेरिकी सधीय सिवधान में शक्ति-पृथक्करण के सिद्धा त को काफी सशीधित कर दिया गया है। सधीय विधानमण्डल — काग्रेस — द्विस्वतारमक है। दोनी स्वत्नो के सदस्यों से नियन्तिम कालों के लिए मित्र तरीकों से नियंचित किया जाता है। सीनेट के सदस्य छ वथ के लिए नियंचित किये जाते है तथा एक तिहाई सदस्य प्रति दो वथ पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं। प्रतिनिधि सभा का काय काल दो वथ है और उसके सदस्य प्रत्यक्ष रीति से जनता द्वारा चुने जाते हैं। दोनों सदन एक दूसरे पर अवरोध (check) के रूप में काय करते हैं। कायपालिका न तो व्यवस्थापिका पर नियर है और न ही जनता पर। सिवधान नियंचित करके अर्थिक शिक्श में काय करते हा कायपालिका को प्रत्यक्ष रीति से त्यांचिक करते अर्थिक शिक्श के स्वव्यंच नियंचित करके अर्थिक शिक्श की विश्वंच नियंचित करके अर्थिक शिक्श की तिश्वंच नियंचित नियंचित करके अर्थिक शिक्श की तिश्वंच नियंचित करके व्यव्यंच की गयी है। राष्ट्रपति के नियंचित के स्विधंच सीनोंध सीनोंधिनर प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति ने भी नियंध सीनोंधिनर प्राप्त नहीं है।

क्षेप नहीं करना चाहिए अपित प्रत्येक को विधि के अधीन अपने विभाग तक ही

सपुक्त राज्य अमेरिका म कायपालिका को विधि निर्माण में अधिकार प्रदान किया गया है। उसे काग्रेस हारा पारित निषिया पर अधिक निर्पेषाधिकार (parual-veto) प्राप्त है। काग्रेस के नाम राष्ट्रपति संदेश भेजकर निषियों का प्रस्तान कर सकता है। इसी प्रकार, व्यवस्थापिका अर्थात काग्रेस को कायपालिका शक्तिया प्राप्त है। सीनेट—काग्रेस का हितीय सदन—को राष्ट्रपति हारा की गयी सिन्ध्या पृत्तयु- किया को दो तिहाई नहुमत से अनुमोदित करने का अधिकार प्राप्त है। युद्ध करने एव सानि स्थापिन करने की शक्तियां काग्रेस को प्राप्त है। सुद्ध करने एव सानि स्थापिन करने की शक्तियां काग्रेस को प्राप्त हैं। स्थिय सरकार के पदा- धिकारियों को काग्रेस की सदस्यता प्राप्त नहीं हो सकती। कायपालिका अर्थात राष्ट्र

¹⁷ Article III

⁸ Kilbourn vs Thompson (S C)

पति आर उसने मित्रमण्डल ने सदस्य कांग्रेस म उपस्थित नहीं हा सन्त । अमिरिसे सर्वोच्च न्यायालय ने यायाधीया की निमुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनट क अनुमानत न की जाती है। लेकिन अमेरिकी सर्वाच्च यायालय का कांग्रेस द्वारा पारित विधिया न वधानिकता नी परीक्षा नरन ना अधिनार प्राप्त है। ततीय पद्धति के बारण प्रक्ति पृथकरण नी किरोत्ता और भी नम दुई है। राजनीतिक दल व्यवस्थानिया एव कायपालिका के मध्य एक कडी ना नाय नरते हैं। राष्ट्रपति एव नर्ग्निस न जब एक ही दल के सदस्य होत हैं, जैवा 1895 स 1911 ई तक या, वी य एक ही दलीं समित के निवंश के अधीन समान उहेरवा की प्राप्ति ने लिए काय करते हैं।

अमेरिकी राज्या की सरकारा म शितः-मृथवकरण अधिक पूण कप म पाग जाता है। व्यवस्थापिना एव यायपालिका के सदस्य तथा राज्यान एवं अय अधि कारी जनता द्वारा निवाचित होते हैं। राज्या के सविधान म दो व्यवस्थाएँ धर्ति-पृथक्करण का अपवाद है। प्रथम, प्राय सभी राज्या म गवनरा का आधिक निषेषा धिकार तथा व्यवस्थापिका को सदेदा नेजन वा अधिकार प्राप्त है। द्वितीय, सभी राज्या के यायालयो म शासन के कार्यों की वैधता को चुनौती दी जा सकती है।

सयुक्त राज्य अमेरिका के सपीय सविधान निर्माताओं ने सविधान में प्रांतियों ने पृथकरण की घोषणा नहीं की है। सिषधान में फाइनर के अनुसार "वितरणासक अनुच्छेद (distributing clause) नहीं या और पूर्ण पृथक्ता की भी व्यवस्था नहीं थी क्योंकि ऐसी अवस्था में शासन चलाना ही अधम्मव हो जाता। '19 सविधान मंबव रोज एस संजुलन (checks and balances) की व्यवस्था द्वारा शासन का व्यवस्थित रूप में संवालन सम्मव हो सका ह।

अमेरिकी सपीम सविधान के आलोचका को सविधान की व्यवस्था स नदीत प्रकार के अधिनायकतान के उदय का भय था। जेम्स भेडीसन ने इस आलोचना हो उत्तर किया है और उत्तर में उसने मोटेस्नयू के तकी को मुक्तहस्त रूप म प्रवार किया है। मोटेस्नयू के विचारों के अनुसार "इगर्लण्ड को सरकार के विभागों में पूर्ण तरह पृथककरण नहीं है। इनमें आधिक सम्या है जो स्वताता के लिए हानि कारक नहीं है। शासन को प्रकृति अतिक्रमणात्मक (encroaching nature) है और इस स्वीकार भी किया गया ह।" मेडीसन नी व्यवस्थापिका की विस्तारवादी गिक्त विद्याप या नयों कि वियोगी शक्ति की व्यारया कठिन है। व्यवस्था पिका विद्याप पर नियंत्रण के माध्यम से कायपालिका के अधिकारा पर नियंत्रण कर सक्ती है। अत मेडीसन की इपिट म व्यवस्थापिका की श्राक्ति के विस्तार ने रोकन की आवश्यकता है। उसने जेफरसन के इस सुभाव को स्वीकार नहीं क्या सासन ने तीन म से दो अम जब सविधान के अतिक्षण के कारण सहायन की मांग कर तो जनता से अपीक की जाय। मंडीसन का तक या कि इससे सविधान की

¹⁹ Finer, H op at, pp 99-100

पवित्रता एवं स्थिरता में से जनता का विश्वास उठ जायेगा । उसने यह सुभाव दिया था कि शासन के आ तरिक ढाचे म ऐसी व्यवस्था की जाम कि "उसके विभिन्न घटक अगा म स्वामाधिक सम्बाध बने रहे और सभी अग यथास्थान रहकर अपने काय कर सके।' व अत संघीय अमेरिकी सर्विधान म पूण शक्ति-पृथक्करण से उत्पन दीपी की दूर करने के लिए अवरोध एव सन्तुलन की व्यवस्था की गयी है। एक अग की शक्ति पर दूसरे अग द्वारा रोक (check) लगाकर शासन की शक्तिया की सातुलित किया गया है। अत अबरोध एव सातुलन का सिद्धा त (The principle of checks and balances) शक्ति प्रथमकरण के सिद्धा त का पूरक है और उसे व्यावहारिक बनाता है।

अत्याचार से रक्षा एव स्वत यता की स्थापना के अतिरिक्त सयुक्त राज्य अमेरिका के सविधान निर्माताओं ने शक्ति प्रथक्करण के सिद्धा त को एक जय कारण से भी अपनाया था। सम्पत्तिशाली, कुलीनत त्रीय एव मध्यम वग को विधान मण्डला में गैर-सम्पत्तिशाली बर्गों के प्रतिनिधिया के बहुमत का भय था। प्रो एक ए केव (Prof F A Cave) के अनुसार सम्पत्तिशाली वग ने अपनी सम्पत्ति एव सुविधा की रक्षा की व्यवस्था शासन को इस प्रकार सगठित करके प्राप्त की है कि अल्प सस्यक सम्पत्तिशाली वग शासन के एक या अधिक अगा का अवरोध एवं सातुलन प्रणाली के अनुसार प्रयोग करके जनता वे ऐसे प्रत्येक काय की जी शक्तिगाली वग के लिए अहितकार हो, रोक सकत है।

स्मरणीय है कि डॉ चाल्स ए बीयड2 ने 'सयुक्त राज्य अमेरिका के सविधान की धार्यिक व्याख्या नामक अपने लेख में यह सिद्ध किया है कि संघीय सविधान ऐसे व्यक्तियों के प्रयत्नों का परिणाम है जिनके आर्थिक हितों को 1777 ई के परिसध (Confederation of 1777) द्वारा स्थापित शासन प्रणाली से क्षति पहुँची थी। अत वे ऐसे सविधान के निर्माण के लिए कृतसकल्प थे जिसके अंतगत उनके हिती

की रक्षा एवं संबंधन हो सके।

फाइनर के जनुसार जमेरिकी सविधान निमाताओं के उपरोक्त सभी उद्देश्या की पूर्ति तो न हो सकी लेकिन मुरय उद्देश्य अवश्य पूण हो सका। वे शासने की शक्तियों को सफलतापूर्वक पृथक कर सके थे। उहींने वायपालिका को व्यवस्था-पिका से पृयक कर दिया। व्यवस्थापिका को दो सदनो मे विभाजित करन से उनमें निरतर प्रतिस्पर्दा की सम्भावना हो गयी तथा व्यवस्थापिका को कायपालिका एव उसके दायित्वा से पुणरूपेण पुथक कर दिया। ब्रिटेन एव फास की विधि निर्माण-प्रक्रिया से सित्र विधि प्रक्रिया एवं वित्त विधेयक प्रक्रिया की स्थापना की । मयक्त राज्य अमेरिका में मि त्रमण्डलीय उत्तरदायित्व का पूण अमाव है। प्रत्येक विमाग का अपना प्रथक दायित्व है।

²⁰ 21

The Federalist, Essay LI, para 1
Beard, CA An Economic Interpretation of the Constitution of the United States, 1913, quoted by K.C. Wheare op cit, pp 67-68

ij

शिनत पृथवकरण के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में अनेको समस्याएँ उत हुई है जिनके नमाधान की आवश्यकता पढ़ी है। समाज की अनक बार निरास भी हो। पढ़ा है। शासन की अय व्यवस्था को नियमित करने के प्रयत्नों के कारण व्यवस्थ पिका एव कायपालिका के मध्य क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर तीव विवाद उत्पन्न हो गंथ। काग्रेस ने कायपालिका की निविधों पर सदय ही नियत्रण रखा है, यहा तक जिल्लावेट का प्रथम राष्ट्रपतिल-काल भी इसका अपवाद नथा। राष्ट्रपति एक दल क और कांग्रेस में बहुनत दूसरे दल का होता है तब दोनों के मध्य गतिरोध के प्राय अधिक अवसर होते है। ऐसी अवस्था में प्राय राष्ट्रपति निर्पेधाधिकार (veto) वे अस्त का लुकर प्रयोग चरता है तथा काग्रेस राष्ट्रपति हारा समर्थित नीतिया पर विधि निर्माण को अस्वीकार कर देती है।

काग्रेस द्वारा अपनी विधियों के उचित किया वयन के लिए स्वत त्र नियामकीय आयोगों की नियुक्त की जाती है जो कायपालिका के निय त्रण से मुक्त होते हैं। काग्रेस ने इन आयोगा की स्थापना करके कायपालिका से पृथक एव स्वत न अदे विधायों सत्ता का निर्माण किया है। व्यवहार में आयोगा को स्थापना से अनेक कि नाइया उत्पन्न हुई है। यदि आयोग राष्ट्रपति से मि न एव विपरीत हुटिकोण रखता है तो वह राष्ट्रपति की योजना को समाप्त कर सकता है और आयोग के क्षेत्र एवं धासन की नीति के सम वय सं सम्बंधित राष्ट्रपति के समी प्रयन्त निष्कल हो जाते हैं।

आयोगो को अपने क्षेत्र म विधि निर्माण के अधिकार भी प्राप्त है। काग्रस द्वारा आयोगा को विधि निर्माण के अधिकार के प्रदर्शकरण को सर्वोच्च ग्यायान्य ने अवैधानिक ठहरात हुए पेट्रोलियम कोड एव इण्डस्ट्रियल रिकवरो एक्ट को अवध् धापित किया था। परतु सर्वाच्च ग्यायाव्य ने वाद मे प्रसासकीय विधि-निर्माण को इस शत पर वध माना कि ऐसी विधिया सुस्पष्ट होनी चाहिए।

सयुक्त राज्य अमेरिका मे अवरोध एव सन्तुलन

शक्ति पृथवकरण म जिंदूट विश्वास रखने वाले विद्वानो की मी यह धारण है कि शिनतयों के विश्वद्ध या निरमक्ष (absolute) पृथवकरण के फलस्वरूप सामत्र को विश्वद्ध या निरमक्ष (absolute) पृथवकरण के फलस्वरूप सामत्र को वाल जा असम्भव ही है। इस सिद्धात के कट्टर समयक मेडीसन की भी यही धारणा थी। इस सिद्धात का यह अय कदापि नहीं है कि विधायी, काम पालिका एव यायपालिका विभागा म परस्पर कोई सम्ब ध ही न हो। मेडीसन की सत्य या वि "तीना विभागा द्धारा सम्बधित होकर जब तक एक दूसर पर नियंत्रण नहीं रक्षा जाता श्वीस्त पृथवकरण का मिद्धात व्यवहार म असम्भव है। शक्ति पृथवकरण का यह अय नहीं है कि तीना विभागा का एक दूसरे पर नियंत्रण नहीं। "अनिविध्वत श्वीसत हमशा खतरनाक होती है। इसी को अस्याचारत न्न नहीं है। श्वीसत के अमरिकी सिवधान

²² Madison The Federalist Essay XIVII

ाओ ने सर्विधान में शक्ति पृथक्करण को स्वीकार करते हुए अवरोध एव न (checks and balances) की पद्धति को भी या यता दी है। अवरोध एव न का अथ यह है कि शासन के प्रत्येक अग को इसरे अगो की शक्तिया में अधि-ादान किया गया है। अमेरिकी सर्विधान म कायपालिका एव विधानमण्डल शेपकर एक दूसरे की शक्तिया में हिस्सा प्रदान किया गया है। उनकी हिण्ट रोध एव स तुलन की व्यवस्था का मात्र उद्देश्य शासन की शक्ति के प्रयोग की r, नियन्तित एव विकेदित (diffused) करना था। अवराध एव सन्तुलन के शासन के प्रत्येक अग की स्वेच्छाचारिता को सीमित एव शक्ति के दूरपयोग को गया है। तीना अग परस्पर एक दूसरे पर निय नण रखते हैं जिसके फलस्वरूप -स तुलन बना रहता है। अमेरिकी सविधान में यह शक्ति सन्तुलन निम्नलिखित

रणा से स्पव्ट है (1) अमरिकी काग्रेस द्वारा पारित विधयका पर राष्ट्रपति की स्वीकृति अनि-है। राप्ट्रपति को दो प्रकार का निपेधाधिकार-वधानिक निपेधाधिकार utory veto) एव परम्परागत निपेधाधिकार (conventional veto)-प्राप्त रम्परागत निषेघाधिकार नो जेवी निषेधाधिकार (pocket veto) भी कहते है। राप्टपति किसी विधेयक को स्वीकृति प्रदान नहीं करता तो काग्रेस द्वारा उसे हाई बहुमत से पुन पारित करन पर वह बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के ही नयम बन जाता है। काग्रेस को राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार ाथ ही राष्ट्रपति को भी काग्रेस के नाम स[्]देश भेजन का अधिकार है।

(2) राप्ट्रपति को नियुक्तिया सिंघयाँ एव समभौते करने का अधिकार है काग्रेस के द्वितीय सदन सीनेट के दो तिहाई वहमत द्वारा इनका अनुमीदन भी यक है। स्मरणीय है कि कांग्रेस न राष्ट्रपति विल्सन द्वारा की गयी वार्साई की

को अस्वीकृत कर दिया था।

(3) राप्ट्रपति देश का सर्वोच्च सेनापति होने के साथ साथ देश की परराप्ट-का सचालक भी है। अत वह अपनी इच्छा से यदि चाहे तो देश की युद्ध म सकता है। राप्ट्रपति बिना उचित कारण के ऐसा न करे इसलिए कांग्रेस की

ाधिकार दिया गया है कि वह युद्ध की घोषणा की पुष्टि करें।

(4) सविधान के अनुसार सर्वोच्च यायालय का कायपालिका एव विधान-र (काग्रेस) से पूरी तरह स्वतात्र रखा गया है किन्तु उसके यायाधीशा की नेत राष्ट्रपति करता है और काँग्रेस का द्वितीय सदन अपने दो तिहाई वहमत से अनुमोदित करता है। कोंग्रेस को यायाधीशा पर महाभियोग लगाने एवं पदच्यत का भी अधिकार है।

(5) राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने, दण्ड को कम करने या स्थिगत करने धिकार है।

(6) सविधान लागू होने के कुछ समय बाद ही सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस

द्वारा निर्मित एव राष्ट्रपति द्वारा जनुमोदित विधिया को सवियान के विपरीत होने पर अवैधानिक घोषित करना शुरू कर दिया था। इसे ही यायिक पुनरीका (judicial review) की सजा दी जाती है।

(7) काग्रेस के दोना सदन-सीनेट एव प्रतिनिधि समा-एक दूसर नी शक्तियों को संतुलित करते हैं। प्रतिनिधि समा द्वारा पारित वित विधेयका म सीनेट को आमूलचूल सन्भोघन का अधिकार है यद्यपि वित्त विवेयक सवप्रथम प्रतिनिधि सम म ही प्रस्तुत किय जाते है। दोना सदनो की विधायी शक्ति समान है परंतु सीनः को कायपालक अधिकार प्राप्त है। सीनेट को प्रतिनिधि समा द्वारा प्रस्तावित महा भियोगा के प्रस्तावा के परीक्षण का भी अधिकार है। इसके अतिरिक्त सधीय व्यवस्था मी शक्ति सन्तुलन का ही एक रूप है। सघीय शासन राज्यों के शासना पर एवं राज्य सरकारें सघीय शासन की शक्तिया पर सातूलन रखते है।

अवरोध एवं संतुलन की व्यवस्था शक्ति पृथकरण को व्यावहारिक रूप प्रदान करती है। प्रो ऑग के अनुसार "एसी व्यवस्था किसी अय सविधान म नही है। शक्ति पृथवकरण की पद्धति अवरोध एव सन्तुलन की व्यवस्था सहित अमेरिकी शासन की मुर्य विशेषता है।" अवरोध एव संजुलन का उद्देश्य शासन क विभिन अगा में एकता एव स तुलन विकसित करना या पर तु विभिन्न विभागां की एकता में बाग हुई है तथा शासन के कार्यों में विलम्ब भी हुआ है। फाइनर के अनुसार "सर्विधान निर्माताजा ने जिन उद्देश्या की कल्पना की थी वे सभी पूण नहीं हो सके है क्यांकि जनके द्वारा नासन के नेतृत्व म एकता (जो वतमान राजनीति की अतिवाय आवश्यकता है) को नष्ट कर दिया गया था। अध्यक्षात्मक शासन की स्थापना करके कार्यपालिका की व्यवस्थापिका स पृथक कर दिया गया तथा काग्रस के दोनो सदनो में निर तर प्रतिस्पर्ग जत्पन हो गयी थी। दोना सदनो मे प्रत्यक मामले म पृथक पृथक नतृत्व बन गये तथा काग्रेस को राष्ट्रपति (कायपालिका) की उपस्थिति एव कार्यों से स्वतात्र कर विश गया था।' 24 कायपालिका एव व्यवस्थापिका मे शक्तियो का विभाजन तथा दोहा में शक्तिया के समावय के उचित साधना के अभाव में शासन के कार्यों म असाधारण विलम्ब होतास्वामाविक था। आरंग एव रेना इस सादम म कथन है कि अवरोर्व एव स तुलन की व्यवस्था न जिसका उद्देश्य शासन म पूण स तुनन एव व्यवस्था स्यापित करना था, शक्ति पृथक्वरण के दोपा को कम करने की बजाय उनकी बढि व"र दी थी। ²⁴ कारविन के अनुसार शक्ति पृथक्करण एव अवरोध और सन्तुलन ^{का} व्यावहारिक महत्व आधुनिक समय म काफी कम हो गया है । राष्ट्रपति की प्रदर्त विधि निमाण नी व्यवस्था न विकास ने कारण विधि निर्माण म पर्याप्त नेतृत्व प्राप्त हो गया है। " अमरिनी सविधान निर्माताना की क्ल्पना से पर राजनीतिक दता के

²³ Ogg Essentials of American Government p 38

²⁴ Finer, H op cit p 101
25 Ogg and Ray Essentials of American Government
26 Corwin SE The Constitution and What It Means Today, p 2

उदय एव विकास तथा उनके कार्यों ने सविषान द्वारा विमाजित शिन्तया का पुत वर्गीकरण सा कर दिया है और एक वडी गीमा तक देश के राजनीतिक जीवन में काय-पातिन का नेतृत्व स्थापित कर दिया है। काग्रेस ने भी सकट काल म राष्ट्रपति के नेतृत्व को स्वीकार किया है। राष्ट्रपति को विधि निर्माण की श्वित्या काग्रेस प्रदान कर सकती है परन्तु काग्रेस अपनी सभी श्वित्या राष्ट्रपति को प्रदान करने का अधिकार कही रखती । यदि काग्रेस अपनी सभी श्वित्या राष्ट्रपति को प्रदान करने का अधिकार कही रखती । यदि काग्रेस होरा ऐसा किया पया, तो सर्वोष्ट "पापालय उसके इस काय को अवैधानिक घाषित कर देगा। अवरोध एव स तुलन को व्यवस्था म राजनीतिक दलो के फलस्वक्ष पर्याप्त सशोधन हुआ है। सविधान जिसे पृथक करता है, राजनीतिक दल उसे जावते हैं।

शक्ति प्रयक्करण एव अवरोध एव स तुलन के सिद्धान्तों ने भ्रम एव विवादा का भी जाम दिया है। काग्रेस एव राष्ट्रपति के बीच विभिन्न प्रकार क सम्बाध रहे है जो राष्ट्रपति एव काग्रेस के सदस्यों के व्यक्तित्व एव तत्कालीन परिस्थितियों में बहुत अधिक प्रमावित होते रह है। विल्सन का कथन या कि सत्ता के विभाजन एव उत्तर-दायित्व की अस्पप्टता के कारण सकट काल म शासन पत्र हो जाता है। जितनी अधिक शक्ति विभाजित होती है, उसी अनुपात मे मत्ता अनुत्तरदायी भी हो जाती है। बतमान काल मे राज्य के कार्यों म असाधारण वृद्धि हुई है। अत सबल प्रमावशाली एव उत्तरदायी शासन की आवश्यकता है। प्रश्न है कि अमेरिका मे प्रचलित शक्ति प्रयक्त-रण के सिद्धा त और अवरोध एवं म तुलन की प्रणाली तथा उत्तरदायी एवं शक्तिशाली शासन की आवश्यकता में समावय कैस स्थापित हो ? इम सम्ब व में विभिन्न सुफाव दिये गये है। बुड्डो बिरसन ने उत्तरदायी मित्रमण्डलीय प्रणाली को श्रेष्ठ मानते हुए उसे स्वीकार करने का सुकाव दिया था। लेकिन अनेक विद्वानी ने अमेरिकी प्रणाली की श्रेप्टता की प्रशसा की है। एक सुभाव यह भी आया है कि कायपालक एव विधायी तत्वो के समुक्त मि नमण्डलो की स्थापना की जाय अर्थात सीनेटर एव प्रतिनिधि सदन के सदस्य राष्ट्रपति के मित्रमण्डल म शामिल किय जायें। एक अप सुभाव यह है कि राष्ट्रपति के मी प्रमण्डल के सदस्यों का काग्रेस के दोनों सदनों में उपस्थित होने, शासकीय प्रस्तावा एव नीतिया के सादभ में विचार व्यक्त करने तथा प्रश्ना का उत्तर देने का अधिकार दिया जाय । कुछ का सुभाव है कि काग्रेस की विधियो को अवैधा-निक घोपित करने के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को निलम्बित कर दिया जाय। इन मुभावों म से किसी को भी कियाचित नहीं निया जा सका है और गक्ति-प्रयक्त-रण, बीपड के अनुसार, आज भी जमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था का प्रधान तत्व है तथा उसकी शासन और राजनीति में निरन्तर अभिव्यक्ति होती है।27

अन्य देशों मे शक्ति-पृथवकरण का सिद्धान्त

येट ब्रिटेन (Great Britain)

मी टेस्क्यू को "क्ति-पृथक्करण की प्रेरणा ग्रेट ब्रिटेन के सविधान सं प्राप्त हुई

²⁷ Beard, CA American Government and Politics, p 16

वी। लेकिन ग्रेट जिटेन भ शक्ति पृथकरण माय नहीं है। यह मो-टेस्क्यू का श्रम था। ग्रेट जिटेन के सविधान के बारे में उसका अध्ययन सही नहीं था। मो-टेस्कूकातान समय में मी नमण्डलीय व्यवस्था का पूण विकास नहीं हुआ था। उस समय व्यवस्था सिम ये मी निमण्डली के सम्बन्धों में एक सीमार तक पर्याप्त पृथकता यी। 18वीं सदी के अन तक मिन्तमण्डल का पूण विकास हुआ था जिसके परिणामस्वरूप विधाय एवं कायपालक काय एक निकास में अधिक्टित हो गये और कायपालिका सन्व पी समस्त कार्यों पर मिन्तमण्डल का तियानण स्थापित हो गया है। बिटिश मिनमण्डल व्यवस्थापिका अर्थात् विटिश ससव के प्रति उत्तरदायी होता है। व्यवहार में हाउस ऑफ काम सं के विश्वास्थात हो मिनमण्डल अपने पर पर रह सन्वता है। मिनमण्डल काम सन्व स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो मिनमण्डल काम काम स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। मिनमण्डल काम सं के विश्वास्थापित हो। मिनमण्डल काम स्थापित हो। मिनमण्डल स्थापित हो। स्थापित स्थापित हो। स्थापित स्थापित हो। काम स्थापित हो। स्थापित स्थापित हो। स्थापित स्थापित हो। स्थापित स्थापित स्थापित हो। स्थापित स्थापित हो। स्थापित स्थाप स्थाप

विदेश समय का उच्च सदन—लॉड समा—गांव भी इंगलण्ड का संबंच्य पुनरावेदनीय यायालय है। नौ न्यायिक सदस्य जि है Lords of Appeal in Ordinary कहा जाता है, इस सदन के आजीवन सदस्य रहते हैं। लांड चारालर लांड समां का अध्यक्ष होता है जो मिनमण्डल का सो सदस्य होता है एव पुनरावेदनीय यायालय (Court of Appeal), उच्च यायालय (High Court of Justice) एवं उच्च यायालय के चा सरी विमाग (Chancery Division of High Court) की भी अध्यक्षता करता है। वह भीवी काउनिस्त की रायिक समिति (Judicial Committee of the Privy Council) का भी सदस्य होता है। स्पष्ट है कि इंगलैंख में शिविन-पुष्पकरण के सिद्धात का नाम तक नहीं है। ससदीय प्रणाली बाले देशी में शासन व्यवस्था जरादायिस्क के सिद्धात पर गठित होती है। वहा शविवयों के पुष्पकरण का प्रका हो नहीं है फिर भी इंगलण्ड में व्यवहार में यायपालिका कार्र पालिका एवं व्यवस्थापिका कीर्र नियानण से मुक्त है।

कास (France)

शक्ति-पृथवकरण के सिद्धा त का विकाध फास म हुआ था। मांटेस्बयू फार्स में निवासी था। यदि रूसा ने फास की जाति को प्रेरणा दी थी तो मोंटेस्बयू के विचारों ने फास के प्रथम सविधानों का स्वरूप निर्धारित किया है। 1789 ई में जाति के निवाला ने जिस सविधान का निर्माण विचा था, उसका आधार हैं। यह पारणा भी कि निवाला ने जिस सविधान नहीं है। फास की राष्ट्रीय समीन ने क्यावन्यापिका एवं कायपाविका शिक्या भी पृथकता वा सिद्धात स्थीकार किया था। यह सियान 1791 ई म लागू हुआ। सविधान म शक्ति पृथकरण की उपेशा मन्य पी कोई व्यवस्था नहीं थी। कायपायिका को विधायी सिवत प्रयान नहीं की गरी सी। राष्ट्रीय समा या मावी महद वा नोई थी सदस्य अपनी सदस्यता के समान्त होने के 4 यप पूष तह मन्यी अथवा लाग के विधी अप पूष दूर नियवत नहीं किया

सकता था। व्यवस्थापिका वा वायवासिका वे अध्यक्ष द्वारा भग नहीं किया जा सकता था। यायाथीन जनता द्वारा निवाचित होते थ। वायवाथीन का अध्यक्ष व्यवस्था-पिवा क कार्यों य माग नहीं लेता था। 1793 ई म यह सविधान असफल हा गया। 1795 ई म नपासिवन द्वारा इसम समाधन विधा गया। उसन राजा वे स्थान पर यनुन वायवास्त्रिया—डायरक्टरी (Directory)—नी व्यवस्था थी। डायरक्टरी के सदस्य व्यवस्थापिवा द्वारा निवीचित होत थ और इस प्रवार पातित पृथकरण व सिद्धा त म सरोधन हो गया।

1816 ई, 1830 ई एव 1848 ई म फा'स व' सविधान विभिन्न स्वस्था म पुनर्जीवित होत रह । 1875 ई म निमित्त फा म क सविधान का स्वस्थ सविधान म निन्न या परन्तु रावित मृबकरण वे सिद्धान्त का अमिर प्रमाय समी सविधाना पर बना रहा । 19वो सदी घर यह तक विधा जाता रहा वि रावित-मृथकरण कि सिद्धान्त का अमिर प्रमाय समी सविधाना पर बना रहा । 19वो सदी घर यह तक विधा जाता रहा वि रावित-मृथकरण के सिद्धान्त न ससदीय यासन-प्रमाणने की स्थापना की गयी कतस्वरूप घवित-मृथकरण के सिद्धान्त न मा मता मही यो गयी थी । तृतीय एव चतुष गणराज्य के अत्यत्त का स ससदीय व्यवस्था यो । कायपातिका सिन्त मित्रमण्डल ॥ निहित थी और उसके सदस्य राष्ट्रीय समा के सदस्य हात थ । मित्रमण्डल राष्ट्रीय समा के प्रति उत्तरदायी हाता था और राष्ट्रीय मना के विवस्त स्वत्य वा । मित्रमण्डल राष्ट्रीय समा के प्रति उत्तरदायी हाता था और राष्ट्रीय मना के विद्यासयन्त अपन पर पर रह सकता था । राष्ट्रपति नाममात्र का अव्यन्त पा एव वाना सदना द्वारा सपुनत अधिकान य चुना जाता था । उध विधि निन्नोय पर निर्पेषान्थियर नात्र नहीं था लेकिन उस बाला सदना द्वारा पारित हिसी नी विधेयक पर पृत विचार की मीम करन का अधिकार प्राप्त था ।

मास क पांचवे गणराज्य (1958 ई) के अन्तरत भी नम्पीन प्राप्ता अपूरा बनी हुई है। का सीसी मित्रमण्डल जिटिया मित्रमण्डल कि मार्ग है। मित्रमण्डल निम्म सदन में प्रति उत्तरणों है औे उनी के प्रमादययन पांचिका है। मित्रमण्डल निम्म सदन में प्रति उत्तरणों है औे उनी के प्रमादययन पांचिका है। पिटिया में प्रमण्डल मी बॉर्ज जो देना मित्रमण्डल उत्तर हाण दिवान मण्डल में विधेयल प्रस्तुत किया जात है और प्रमान की की मीति ही की वापान की कि उत्तरणों है उत्तरणां है। परन्तु पर्वे देशों की व्यवस्था में कुछ महत्वपूष्त जन्म में कि किया मित्रमण्डल के प्रमान की मित्रमण्डल की प्रतिवादी और कि उत्तरणां के निवास हो। परन्तु पर्वे के पर्वे में प्रमान की प्रवास की प्र

काइनर व अनुसार अन्य स्थानिक विशेष दर व स्थानिक स्थानिक विशेष दर व स्थानिक स्थानिक विशेष दर व स्थानिक स्थानिक

के सविधाना म यायपालिका को व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित विधिया को अवधानिक घोषित करन का अधिकार नही दिया गया है। द्वितीय, सवा-काल म किये गय अप राध या भूल के लिए किसी राजकीय कमचारी की जाच एव उन्हें दण्डित करने की अधिकार सामा य न्यायालय को नही दिया गया अपितु ऐसे अपराधा के लिए प्रशास कीय विधि एव यायालयों की पृथक से स्थापना की गयी । ऐसी ही स्थित जमनी में हे लेकिन इमलण्ड मे इससे सवया मिन व्यवस्था है। अ विक्त-पृथवकरण क सिद्धाल का फ्रांस में स्वामाविक परिणाम प्रशासकीय यायालया की स्वामना थी। Council of State (Conscil d' Estate) फास म सर्वाच्च प्रशासनिक यायालय है। इस "यायालय को स्थानीय एव के द्वीय कमचारिया के नागरिका के प्रति अपराध या भूला के लिए क्षेताधिकार प्राप्त है।

सोवियत इस (USSR)

रूस के 1936 ई के स्टालिन सविधान के अत्तगत स्यापित शासन व्यवस्याम शक्ति पृथककरण के सिद्धात को मायता नहीं दी गयी है। विशि सकी ने 'सोवियत सविधान एवं विधि' नामक अपनी पुस्तक म यह मत ब्यक्त किया है कि संगुक्त राज्य जमेरिका एव यूरोप म शक्ति-पृथक्करण के सिद्धात द्वारा कायपालिका की प्रमुखता को छिपाने का प्रयास किया जाता रहा है पर तु कायपालिका की प्रमुखता को रोका नहीं जा सका है। फाइनर को विशि सकी के इस क्थन में कोई सत्यता नहीं दिलायी देती है। 8

रुस म मित्रमण्डल सुप्रीम सोवियत के प्रति उत्तरदायी है। प्रेसीडियन मी अत म सुप्रीम सोवियत के प्रति ही उत्तरदायी है। मिनमण्डल के सदस्य सुप्रीम सोवियत के सदस्य होत है और वे विधि निर्माण में महत्वपूण भूमिका अदा करते हैं। जत रूस मे शक्ति पृथक्करण को स्वीकार नहीं किया गया है।

भारत (India)

भारत का नवीन सविधान (1950) ससदीय प्रणाली की स्थापना करता है। मिनमण्डल (नायपालिका) के सदस्य ससद के सदस्य हात ह और मित्रमण्डल लोक समा के प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्रपति नाममान की कायपालिका है तथा अप्रत्यक्ष रीति से राज्यो की व्यवस्थापिकाआ एव भारतीय ससद के निवाचित सदस्या के निर्वा चन मण्डल द्वारा चुना जाता है। मित्रमण्डल अपने पद पर लाकममा कं प्रसादप^{म त} ही रह सक्ता है। प्रधानमात्री को लोकसभा के विघटन की माग करने का अधिकार हैं। राष्ट्रपति सर्वाच्च यायालय के यायाबीक्षा की नियुक्ति करता है लेकिन संसंद को उन पर महामियोग लगान का अधिकार प्राप्त है। कायपालिका को क्षमा प्रशन करने सम्बाधी कुछ "यायिक अधिकार भी प्राप्त हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महामिया^ग

²⁸ Finer, H op cit, p 104 29 Ibid , p 106

की जांच का अधिकार भारतीय ससद का है। सर्वाच्च यायालय को ससदीय विधिया एव कायपालिका के कार्यों का अवैधानिक घोषित करने का अधिकार है।

भारत की शासन-व्यवस्था ब्रिटिश ससदीय व्यवस्था पर आधारित है। उप-रोक्त तथ्या स यह स्वयसिद्ध है वि भारत की शासन-व्यवस्था म शक्ति प्रयक्करण को मा यता नहीं दी गयी है।

निव्य प

व्यवहार म शक्ति पृयक्करण के सिद्धान्त म पर्याप्त सशोधन हुजा है। अमेन रिकी सविधान-निमाताओं ने शक्ति पृथक्करण के दोपा के परिहार के रूप म ही अब-रोव एव सन्तुलन क सिद्धान्त को स्वीकार किया है। शक्ति पृथवकरण एक सीमा तक ही उचित है। गेटेल के अनुसार "अपन चरम रूप म शक्ति पृथक्करण तथा अवरोध और स तुलन सुशासन के लिए खतरनाक है। बहुत अधिक शक्ति पृथवकरण से राज्य की विधिक रूप म अभिव्यक्त इच्छा के प्रशासन हेतु आवश्यक एकता एव सहयोग म बाधा उत्पन होती है और बहुत अधिक अवरोध एव सातुलन शासन म गतिरोध एव सघप उत्पन कर देता है जिनसे सुशासन एव क्षमतायुक्त व्यवस्था के माग मे बाधाएँ पदा हो जाती है।"⁵⁰ शासन के विभिन्न जया के एक से ही उद्देश्य होत है अस शासन की सफलता के लिए विभि न जगा म वास्ति सहयोग आवश्यक है।

इस सिद्धात का अत्यात व्यापन प्रभाव पढा है। लास्की ने इस सम्याध म तिखा है कि "बायपालिका स यायपालिका की स्वत नता व्यक्तिया की स्वत नता के लिए भावश्यक है। शक्ति पृथवकरण के सिद्धात की उपयोगिता एव उसका अधिकाश महत्व इस विशेषता म निहित है कि वह यायपालिका की स्वत नता पर सवाधिक वन देता है। यदि कायपालिका अपनी इच्छानुसार यायिक निषय दन लग ता वह राज्य का पूर्ण स्वामी वन जायेगा।"31 आज प्राय सभी सबैधानिक दशा म वायपालिका की स्वताताका सिद्धात माय ह।

³⁰ Gettell Political Science, p 216 31 Laski A Grammar of Politics, p 542

एकात्मक एव सघात्मक राज्य UNITARY AND FEDERAL STATES

शक्तियो का विभाजन

शासन की समित के कार्यों के आधार पर विमाजित करने के सिद्धा त—शक्ति पृथक्तरण—का अध्ययन हम पाचवे अध्याय म कर चुके हैं। लेकिन आधुनिक राज्यों में क्षेत्र को हिन्द से भी शासन की धनित को विमाजित करने की आवस्यकता अपुनर्व हुई है। विसाज एवं विस्तृत राज्यों का सासन एक ही के द्र से नहीं हो सच्छा। सुमर्व सुमाजित के लिए यह आवस्यक है कि राज्य को पृथक-पृथक प्रशासनिक इकाइयों में विमाजित कर दिया जाय और प्रत्येक को अपने की म शासन के कुछ विशिष्ट वार्षित सौपे जार्में। इन प्रशासनिक इकाइया का अपना शासनम्बर्धन में होता है। इस आधार पर राज्य को के द्रीय एवं स्थानीय शासना अथवा सचीय एवं क्षेत्रीय शासनों में विमाजित किया जाता है। यही एका मक एवं सथासनक शासना में भेद का आधार है।

शासन की शनितया के विमाजन की आवस्यकता न केवल राज्या के विशाज का कार के कारण ही वाछनीय है अपितु इस हथ्यिकाण से भी जिसत है कि शासन को का के वायति है कि शासन के क्षेत्र हायित्वी का सम्ब थ ऐसी समस्याओं से है जो समग्र राज्य के हित के न हों के वे वासन स्थानीय महत्व के होते हैं। "यदि किसी राज्य में शासन के समस्त कार्य की किया सरकार के द्वारा ही किये जायें तो मुशासन की हृष्टि से उसका काम मार अधिक होगा और शासन में अनावस्थक व्यय एवं विलाग होगा। इसके अतिरिक्त यह प्राथम प्राथम है कि छोटे-छोटे समाजों को उनसे सम्बच्धित मामला में प्राथम का अधिकार दिया जाय क्यों के प्रस्थात व्यक्तिया हारा अपने से सम्बच्धित मामलों का प्रशासन अधिकार दिया जाय क्यों के सम्बच्धित सम्बच्या सम्बच्धित सम्बच्या सम्बच्धित सम्बच्या सम्बच्धित सम्बच्धित सम्बच्धित सम्बच्धित सम्बच्धित सम्बच्धि

क्षेत्रीय आधार पर शासन सत्ता के विभाजन से सम्बद्धित अनेक समस्याए हैं। जैसे−-क्षेत्रा का विमाजन किस प्रकार हो, यह किस सत्ता के द्वारा निश्चित किया

¹ Gettell Political Science 1956, p 227

जाय, क्तिनी शासन-सत्ता हर क्षेत्रीय इकाई को प्रदान की जानी चाहिए हर क्षेत्र म किस प्रकार की सरकार स्थापित की जानी चाहिए, जादि।

एकारमक एव सघारमक राज्या का भेद उपयुक्त प्रथम प्रश्न पर आघारित है अर्थात क्षेत्रीय हिन्द से द्वासन-सत्ता का विशेषकर राष्ट्रीय एव स्थानीय सरकारा के रूप म विभाजित करने का अधिकार विधिक हिन्द से किस समा का प्राप्त है ? सत्ता विभाजित करने की मुस्यत दो प्रकार की पद्धति है फलस्वरूप दो प्रकार के शामन होते हैं । एक पद्धति के अत्तानत सविधान द्वारा शासन की सम्पूण सत्ता के प्रीय सरकार को प्रमान की जाती है जा उस सत्ता का अपनी इच्छानुधार क्षेत्रीय उपमागा को प्रवान करता है । इन खेंनीय उपमागा का के द्वीय सरकार को अपनी स्वेच्छा से निमाण करती है और सामाय विधि द्वारा इनके कीन तथा अधिकारों में स्वेच्छा से परिवर्तन कर करती है । इस प्रणाली को एकास्मक सरकार वहते है । इस्परी पद्धति के अनुसार राज्य के सर्विधान द्वारा स्थप्ट रूप से राष्ट्रीय एव क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शासन की सत्ता कि सरकार के स्वय शासन की सत्ता विमाजित होती है । इस पद्धति के अन्तगत राष्ट्रीय सरकारों और के स्था शासन की सत्ता विमाजित होती है । इस पद्धति के अन्तगत राष्ट्रीय सरकारों और देश यवस्था में एकाको कोई परिवर्तन ही कर सकते है । शासिक्या का पुत्रविभाजन सविधान में सशो धन द्वारा ही सम्भव है । इस प्रणाली के अन्तगत स्थापित व्यवस्था को सधीय व्यवस्था या सम शासन कहत हैं ।

सक्षेप म जिन राज्यो म सम्मूण शासन-सत्ता सविधान द्वारा के द्रीय सरकार म अधिष्ठित होती है, उ ह एकात्मक शासन कहत है, और जिन राज्या म सविधान द्वारा शासन की सत्ता को के द्रीय एव स्थानीय सरकारों में विभाजित कर दिया जाता है उ ह सबीय शामन (federal government) कहते हैं। इस अध्याय म नमय एकात्मक एव संधारमक सरकारा का अध्ययन किया जायंगा।

एकात्मक शासन

विभिन्न विद्वानों ने एकारमक सासन (Untary Government) की मिन भिन्न परिमापाएँ दी है। सी एक स्ट्राय के अनुसार "एकारमक शासन एक के द्रीय सरकार के अधीन सगठित होता है अथींत् के द्रीय शासन द्वारा प्रशासित क्षेत्रा तगत जिलो को जो भी शक्ति प्राप्त होती है वह उन्ह के द्वीय सरकार को उक्क्षिय पर मत बाती है तथा के द्वीय सरकार सर्वाच्च होती है और अपने क्षेत्रों को शक्ति प्रदान करने वाली विभि को उस पर कोई नियं नण नहीं होता।" अस्त एकारमक राज्य म आयसी के

² Gettell op est, p 228

³ Ibid , p 228

A unitary state is one organised under a single central government that is to say, whatever powers are possessed by the various districts within the area administered as a whole by the central government and the central power is supreme over the whole without any restrictions imposed by any law granting special powers to its parts "—Strong ob sit, p 63.

अनुमार "राज्य की शक्ति एक हश्व्य मर्वाच्च सत्ता ससद या जार (राजा) के हाया म केंद्रित होती है।"

गानर के अनुसार एकारमक द्वासन म "वासन की द्वित्त सिवधान द्वारा एक के द्वीय अग या अगा को प्रदान की जाती है एव उसी से स्थानीय सरकारा का अधि कार या स्वायत्तता (जिसका वे प्रयोग करती हैं) तथा बस्तित्व की प्राप्ति हाती हैं। एकारमक सरकार की एक पुर्य विद्येपता यह है कि के द्वीय द्वासन तथा अधीनर के नेया के प्रयास करते हैं।

फाइनर के अनुसार 'एकात्मक राज्य में सम्पूण शासन सत्ता एवं शक्ति एक ही केंद्र के हाथा में होती है तथा उसकी इच्छा एवं अधिकारी सम्पूण क्षेत्र में सब

क्षक्तिमान होते हैं।"⁷⁷ उपयुक्त परिमाषाओं के आधार पर एकात्मक सरकार के सामाय नक्षण निम्मवत है

एकात्मक शासन मे---

 एक राज्य मे एक ही शासन होता है। शासन सत्ता का एकसान स्रोत एव इच्छा होती है तथा के द्रीय एव स्थानीय सरकारा म शक्तियो का कोई सवधानिक विभाजन नहीं होता है। स्ट्राग के अनुसार के द्रीय सरकार की शक्ति अनियित्ति होती है।

(2) के द्वीय सरकार द्वारा प्रशासकीय सुविधा की हिन्द से क्षेत्रीय प्रशासनी की निमाण किया जाता है। इह विमित्र देशा म मिन मिन नामा से पुकारा जाता है। जस—िहपाटमा (कास म), प्रान्त (ब्रिटिश भारत मे), काउण्टी (इगसण्ड म), आरि ।

(3) स्थानीय सरकारे ने द्वीय सरकार के द्वारा निर्मित होती हु और उनने स्वायत्तता एव सत्ता का निधारण भी उही के द्वारा होता है। एकात्मक राज्य में

स्थानीय सरकारे के दीय सरकार की अभिकर्ता मात्र होती है।

(4) स्थानीय या क्षेत्रीय सरकारा को मौलिक सन्तिया प्राप्त नहीं होती। स्ट्राम के अनुसार एकात्मक सरकार की दो प्रमुख विशेषताएँ हैं—प्रवम्न, व द्वीय ससद (व्यवस्थापिका) की सर्वोच्चता, द्वितीय, अय सर्वोच्च निकायो का अनाव (the absence of the subsidiary sovereign bodies) 18 स्ट्राम न इन दोना

^{5 &}quot;Unitarianism in short means the concentration of the strength of the state in the hands of one visible sovereign power, be that power Parhament or Czar

⁻Dicey Law of the Constitution, | 157

⁶ Garner Political Science and Government, p 317

⁷ Finer H op at, p 116 8 Strong, C F op at p 84

विरोपताओं की व्याच्या करत हुए, यह स्पष्ट किया है कि सविधान द्वारा एकात्मक राज्या म ने द्रीय व्यवस्थापिकाओं को विधि निर्माण के सर्वांच्य एक निरपक्ष अधिकार होता हैं। इसके अतिरिक्त एकास्मक राज्या म सधीय राज्या को माति राज्य मा क्षेत्रीम सरकार नहीं होती जो सविधान हारा अपने कर म स्वायत्ताक प्रयोग करती हो। सपीय राज्या म दकाद्या को प्राप्त सिक्तियाँ सविधान द्वारा प्रदत्त होती है अत मधीय तरकार दारा जनम कभी या वृद्धि नहीं की जा सकती।

एकारसक राज्य के जुछ उदाहरण इसलण्ड, पूजीलण्ड, आयरलण्ड दक्षिणी अफीना, मेलजियम, फास एव इटली है। इन सभी राज्या म के द्रीय निधि-निर्माण सत्ता पर कोई नियानमा नहीं है। के द्रीय सरकार सत्ता का एकमान स्रोत हीती है। इसलण्ड में स्थानीय शासन पयाप्त शिवदााली एव स्थायत्तान्त्रान्त हैं लेकिन के द्रीय सरकार पर इसका कोई विधिक-नियान्त्र नहीं है। स्थानीय शासन के निणयों को के द्रीय सरकार स्वेच्छानुसार बदल सकती है। इसलण्ड में स्थानीय शासन विधि निमात्री निकाय न होकर उपनियमों (rules and by laws) का निमाण करन वाले निकाय होते है।

गानर कं अनुसार "एकात्मन कासन का सार स्थानीय स्वशासन का अभाव है। यदि कुछ स्थानीय स्वनामन हं भो तो वह केन्द्रीय मरकार द्वारा प्रदत्त हं और उसे वह अपनी दच्छानुसार सीमित या समान्त कर सकती है।"

एकात्मक शासन के गुण

- (1) एकारमक शासन के अतागन सम्मूर्ण देश मे प्रशासनिक एव विधिक एकता तथा एकीञ्चत शासन की स्थापना सम्मव होनी है।
- (2) गामन का व्यय अपेक्षाकृत कम होता है क्योंकि एकात्मक राज्य में सप धासन की तरह दूहरा भासन-व्यवस्था नहीं होती।
- (3) लघु एव सम्यता तथा सास्क्रानिक एकता में युवत राज्या के लिए एका सक धामन सर्वाधिक उपयुक्त है। ये सरकारे धावितधाली एव सुष्टढ होगी है। सारे देश में एक स ही कानूना एव आदेशा का पालन होता है।
- (4) राष्ट्रीय सकट के ममय एकात्मक संन्कारे अधिक शस्तिशाली प्रमाणित हुई है। अत्तराष्ट्रीय एव सुरक्षा सम्ब वी दायित्वा का पालन भी वे अधिक मफलता-प्रवक कर सकती है क्यांकि राज्य के मंत्री अधिकारी उनकी अधीनता म हात है।
- (5) राष्ट्रीय एकता की भावना के विकास व लिए एकात्मक राज्या म उपगुक्त वातावरण होता है। प्रावेशिक एव स्थानीय मक्ति की मावनाओं को उमरने भा अवसर नहीं मिलता और न विषटनकारी तत्व ही सिक्य हो पात है। एक्ल नागरिकता के कारण राष्ट्रीय एकना को भी वल मिलता है।
- (6) आधिक विकास भी शीझता एव सरलता स सम्मव होता है। एक सी नियोजित नीति सारे देश को एक आधिक इकाई मानकर क्रियान्वित नी जा सक्ती है।

एकात्मक शासन के दोप

(1) एकात्मक शासन म सक्तिशाली प्रा तीय एवं क्षेत्रीय संस्थाओं का अगर्व रहता है । स्थानीय समस्याओं एवं नीतियों की व्यवस्था के द्रीय अधिकारिया द्वारा की जाती है। के द्रीय अधिकारिया की स्थानीय समस्याओं का प्याप्त ज्ञान नहीं होता, फलस्वरूप स्थानीय हिता की पुण रक्षा सम्भव नहीं होती है।

(2) एनात्मक शासन निशाल आकार एव व्यापक जनसरया वाल राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। इससे प्रशासन में शिषिकता जा जाती है तथा अनावसक विकास होता है। इसमें लालफीताधाही एवं नौकरश्वाही का बोसवाला होता है। ससे में प्रशासनिक के द्वीकरण एवं एकस्पता होती है।

(3) धम, भाषा, नस्त आदि की विभिन्नताओं से युक्त राज्या में एकासक शासन सफल नहीं हो सकता। प्रत्येक सास्कृतिक समूह का अपना व्यक्तिरव होता है। एकात्मक ग्रासन के अन्तगत वे अपनी परम्पराओं अथवा रीतियों के अनुरूप अपनी विकास नहीं कर पाते।

(4) इस शासन के अतगत स्वानीय जनता म पहल करन की क्षमता की विकास नहीं हो पाता और न सावजनिक कार्यों में जनता की इचि ही उत्पत्न ही पाती है। गानर के अनुसार "इस व्यवस्था के अधीन स्थानीय शासन की शक्ति कमजार ही जाती है और के दीकृत नाकरशाही का विकास होता है।"

(5) एकात्मक शासन प्रणासी लोकता व के सिद्ध त के विष्क है। गातर के अनुसार इस प्रणासी को कभी-कभी के दक्षत (centralised government) को भी सन्ना दी जाती है यद्यपि यह दोनो ही समान नहीं है लेकिन एकात्मक शासन अधिकतर के दक्षत होता है। अव्यध्यिक के दीकरण के इस दोष को विकेटित व्यवस्था हो प्रीत्साहन देकर कम करने का प्रयत्न किया गया है।

फान्स म एकारमक वासन है। वासन की सम्पूण सत्ता परिस स्थित के नी सरकार म अधिष्ठित है। के द्रीकरण की इस व्यवस्था को शिथिल बनाने के लिए अहें कदम उठाये गये है। वे द्रीय सरकार न अनेक प्रशासनिक मामला की विपादमा एवं कम्मून के प्रीकेवट, पण प्रोफेवट, मयर एवं पुलिस कमिस्तर आदि अधिकारिया के सम्प्रत के प्रीकेवट, वण प्रोफेवट, मयर एवं पुलिस कमिस्तर आदि अधिकारिया के स्थानतित कर दिया है। इसस परिस स्थित के द्रीय शासन म के द्रीकरणजीति अध्यासक कम हुई है। लेकिन समस्त स्थानीय अधिकारिया की नियुक्त परिस स्थित के द्रीय सरकार द्वारा है। की जाती है और व उसके अमिकता के रूप म ही काय करता है। फास म दिक द्रीवरण को व्यवस्था इस सीमा तक ही है कि वहाँ स्थानीय स्वयासन की स्थापना की यथी लेकिन स्थानीय अधिकारिया की शास्त्रयी पर्यापत सीमित है और ने द्रीय मरकार का उन पर व्यापन प्रशासनिक नियंत्रण है। गहा स्थित सभी एकारमक राज्या नी है।

सघात्मक राज्य

मधारमर शामन (Federal State) एकारमक शासन का विलाम है । इसम

शासन की सत्ता सविधान द्वारा के द्रीय एव स्थानीय या क्षेत्रीय (local or regional) सरकारों में विमाजित होती है और के दीय सरकार स्वेच्छा से स्थानीय या क्षेत्रीय सरकारा के सविधान प्रदत्त अधिकारा एव शक्तिया को समाप्त या परिवर्तित नही कर सकती । ऐसे परिवतन सविधान में संशोधन द्वारा ही सम्भव है । विभिन्न विद्वानी ने सघारमक झासन की निम्नलिखित परिभाषाएँ दी है

मो टेस्बयू (Montesquieu) के अनुसार सच राज्य एक प्रकार का "ऐसा समभौता है जिसम अनेक छोटे-छोटे राज्य एक ऐसे बड़े राज्य मे विलीन हो जाते है जिसकी उनके द्वारा स्थापना की जाती है।"

क्रीमेन के जनसार "सधीय शासन मे पूण विकसित हप्टि से एक तरफ ती संघ के सभी सदस्य शासन से सम्बाधित मामलों में पूण स्वतात्र होने चाहिए और दूसरी तरफ सभी सदस्यों को सामृहिक रूप से सम्बर्धित विषया में एक सामा य सत्ता के अधीन होना चाहिए। प्रत्येक सदस्य (राज्य) अपने क्षेत्र में पूण स्वत त्र होना चाहिए परत एक दूसरा क्षेत्र भी होता है जिसमे उसका पूरा अस्तित्व ही तिरोहित ही जाता है। 1710

डायसी के जनुसार 'सघवाद का अब है कि राज्य की शक्तियों को ऐसे अनेक समान निकायों में विभाजित किया जाय जो सर्विधान की अधीनता एवं नियात्रण में काय करते हो। ^{'11} सभीय शासन राजनीतिक व्यवस्था है जिसके द्वारा राष्ट्रीय एकता

एव राज्या के अधिकारा में सम वय स्थापित किया जाता है।

प्रो ऑग एव रे के अनुसार "संघीय शासन प्रणाली राजनीतिक संस्थाओ की एक ऐसी व्यवस्था है जिसम सत्ता के दो के द्र-एक के द्रीय तथा दूसरा क्षेत्रीय-होते ह । किसी अय व्यवस्था की तुलना में इस व्यवस्था में शक्तियों एवं वामित्वों के स्पष्ट विभाजन की जावश्यकता होती है। सविधान द्वारा निर्धारित व्यवस्था किसी निरपेक्ष राजनीतिक वार्तालाप का परिणाम नही होती अपित अपने समय की मागका परिणाम होती है।"1

हैरीसन मूर के शब्दों में "सधीय शासन म किसी राज्य की सत्ता दो प्रकार के सगठना म विभाजित होती है-(1) के द्वीय शासन, और (11) अनेक स्था नीय सरकारे । दोनो एक दूसरे से इस सीमा तक पृथक होती हैं कि कोई किसी को समाप्त नहीं कर सकत और न एक दूसरे के सविवान निर्धारित क्षेत्राधिकार का अतिनमण ही कर सकते है।"18

गानर के जनसार "सधात्मक शासन एकात्मक शासन का विलोध है। इसकी मर्य विशेषता यह है कि राज्य की विधायी, शासन एवं प्रशासन की सत्ता राजधानी

Freeman, E A History of Federal Government, p 3 10 11

Dicey, A V Law of the Constitution, p 157
Ogg and Ray Introduction to American Government, 1956, p 45 12

Moore, W Harrison The Constitution of the Commonwealth of Australia, 1910, p 68

ने के द्रीय अग मे सगठित न होकर केन्द्रीय सत्ता एव सघ की घटक इकाइया क अधिकारियों के हाया में विमाजित होती है। प्रत्येक राज्य अपने क्षेत्राधिकार म स्वतान होता है और के द्रीय सरकार का उन पर कम या कोई नियानण नही होता। जपने क्षेत्र मे राज्य विधि निर्माण तथा शासन एव प्रशासन के मामला म स्वत प्र होते है और स्थानीय आवश्यकताओ एव हिता के जनुरूप ही काय करते हैं थत 'फ्डेरल प्रणाली' के द्रीकृत शासन एव स्थानीय शासन के सम वय का प्रतिनिधिल करती है। '14

मेरियट ने सघ व्यवस्था को मिश्रित या संयुक्त राज्य की सज्ञा दी है। 15 विलोबी इसे बहशासनत जवादी राज्य कहता है।16

सर रॉबर्ट गटन के अनुसार "जिस शासन मे सप्रमुता या राजनीतिक सती के द्रीय एव स्थानीय सरकारों में इस प्रकार विमाजित हो कि दोनों अपने-अपने क्षत्री मे एक दूसरे से स्वतात हो, तो वह सधारमक शासन है। "17

हैमिल्टन के अनुसार "सधीय राज्य राज्यो का सध है जो एक नय राज्य का

निर्माण करता है।"

स्ट्राग के अनुसार सघारमक राज्य वह राज्य है "जिसम अनेक समान (coor

dinate) राज्य सामा य उद्देश्य के लिए एकीकृत हा जायेँ।"18

हरमन फाइनर के अनुसार "सघीय राज्य म सत्ता एव शक्तियो का एक माग स्थानीय क्षेत्र मे और दूसरा भाग के द्रीय सस्था म अधिष्ठित होता है जिनका निमाण जानवूभकर पहले से स्वतान स्थानीय क्षेत्रों के सथ (association) द्वारा हाता है।"19

के सी ह्वीयरे नो समात्मक शासन व्यवस्था का एक अधिकृत विद्वान माना जाता है। ह्वीयरे के अनुसार सघ (Federation) राजनीतिक चित्तन के क्षत्र वी यहुर्चीचत विषय है तथा इसकी व्याख्याएँ बहुत कम स्पष्ट है । ह्वीयरे के अनुसार सघारमक शासन वी कोई परिमापा उस समय तक प्रथ या मा य नही मानी जा सर्डी जय तक उसम समुक्त राज्य अमरिका के सविधान को स्थान न दिया गमा हा। राव नीतिक सगठन का जो सिद्धात समुक्त राज्य अमरिका के सविधान म पामा जाता है। यह सपीय शासन वा सिद्धात है। ह्वीयर न सघीय सिद्धात जी परिमापा दते हुए वहा है कि सधीय सिद्धात का अथ सत्ता क विमाजन की ऐसी पद्धति से है जिसके द्वारा सामान्य (general) एव क्षेत्रीय (regional) सरकारें अपन क्षत्रा म सावनाय होत हुए भी सहयांगी एवं स्वत त्र (coordinate and independent) हाती हैं।

Garner op cit pp 381 82 Marriot The Mechanism of the Modern State Vol II, p 382 15

Willoughby The Government of the Modern State, p 261 16 Quoted by Wheare, K C Federal Government, p 33 17

¹⁸ Strong C F op at p 64 19 Finer, H op at, p 10 20 Wheare, k C op at, p 10

इस सिद्धा त का विश्लेषण करत हुए होग्यर ने यह स्पष्ट किया है कि प्रत्यक सरकार 1 1 को अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहत हुए द्वार के हस्तक्षेत्र सं मुक्त हीना चाहिए। इसी एकात्मक एवं सघात्मक राज्य | 143 7 विद्वात के आधार पर ह्वीयरे ने तथीय धावन को व्यारमा करते हुए विद्वा है कि 7 पित एक वासन प्रणाली म मुख्य रूप से सामा य एव के त्रीय सत्तावा म सक्तिया का विमाजन किया जाता है और प्रत्येक सत्ता अपने क्षेत्र म द्विपरे के साथ साथ रहते हुए भी स्वतंत्र है तो वह सासन संघीय है। "श्र लीयरे उपर्युक्त संघीय सिदा त को सविधान म अगोकृत करता ही पर्याप्त गृही मानत । उनके अनुसार शासन का स्वरूप संधीय है अथवा नहीं, यह उसके किया वयन पर ही निमर करता है। अत ह्वीयरे के अनुसार संघीय सिद्धात को शासन म व्यवहार रूप म और सिद्धान म सिद्धान्त नियाचित किया जाना चाहिए। सधीय राज्य का सविधान एवं सरकार दोनो ही सधीय होने चाहिए। अत ह्वियरे ने संघीय शासन एवं संघीय सर्विधान मं अतर या भेद किया है। एक देश का संविधान संघीय हो सकता है पर तु यह सम्भव है कि व्यवहार म वह सिविधान इस प्रकार काय करता हो कि उसे सधीय नहीं कहा जाना चाहिए या यह भी सम्भव है कि गर-चंघीय सविधान इस प्रकार नियाचित किया जाता ही कि वह सधीय सरकार का उदाहरण प्रस्तुत करे।

जिप्युक्त सभी परिमापाओं म से एक व्यक्ति निकलती है कि सधीय राज्य मे है त्रीय एव स्थानीय या क्षेत्रीय सरकारा को अपने अपने क्षेत्रा म स्वतः त होना बाहिए तया के त्रीय एवं स्थानीय संस्कारों को एक हसरे के क्षेत्रा म हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन यह मत केवल आधिक सत्य पर ही बल देता है। फाइनर ने परिमापा 1 सम्बधी इस कमी की ब्याल्या करते हुए लिखा है कि "एक बार जस ही कुछ विश्वास्त बाता को दूसरी नातो से पथक करने के उद्देश्य स सामा य नाम प्रवान कर दिया जाता हैं, वे क्खुएँ स्वत ही सम्प्रता के निए किरमात हो जाती है लेकिन ऐसा होता नही है।" फाइनर का ग्रह कथन संघीय शासन की परिमापा पर भी लागू होता है। फिर सबीय शासन भी हर राजनीतिक सस्या की न्नांति निकास का परिणाम है। कोई मी दों तपात्मक शासन एक से नहीं होते और न कि ही दो सभीय सरकारों का एक नकार से जदय या निकास ही हुआ है। हर सिनिधान सम्बन्धित देश, काल एवं जनता और जनकी आवस्त्रकृताना का परिणाम होता है। संघात्मक राज्या के संविधान भी इसके अपवाद नहीं है।

इसने अतिरिक्त समात्मक शासन एक जहस्य की पूर्ति का साधन है। यह किसी समाज की विशेष राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में मुसासन के हेंचु स्वापित कारत वा विकास अवस्थातक एक वासावक वास्तवका व अवस्था के एउट रामाच्या के उत्तवका उद्देश्य के विपरीत हो।

^{का विश्व}रात है। । भी एत ने सी विते ने समवाद कें व्यावहारिक रूप के आपार पर परिमापा Wheare K C op at, p 33 21 22 Ibid, p 10

देने का प्रयत्न किया है। प्री क्लि ने 1789 ई में अमेरिकी संघीय व्यवस्था की कायप्रणाली का अध्ययन व्यावहारिक हृष्टि से किया है। वे इस अध्ययन में प्री ए एवं जिस (Prof A H Brich) के विचारों से सहमत हैं। बिच के अनुसार अपने अपने किया में किया ते कि उत्तर होते हुए भी संघीय राज्या की के द्वीय एवं राज्या की सरकारा में परसर सहयोग की अधिकाधिक अवित्त पाल्यों जाती है। अब जिस्स संघासक शासन या राज्य की किसी ऐसी परिमाधा को स्वीकार नहीं करते हैं जिसमें के द्वीय एवं राज्यों में सरकारों की अपने-अपने क्षेत्र में के बल स्वता असा पर बल दिया गया हो। प्री जिस संघ की कै द्वीय एवं क्षेत्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों से सहयोग की अवस्था को संघवाद की एक अनिवाध विशेषता मानते हैं। एम जिसी खिलों ने संघवाद की निम्मालिखित परिपादा दी हैं

'सपवाद शासन की वह प्रणाली है जिसम क्षेत्रीय सत्ताएँ पारस्परिक का है निमर राजनीतिक सम्ब को में आवढ़ हाती है। इस प्रणाली में ऐसा स पुलन रहां जाता है कि कोई भी सरकार एक इसरे को जादेश नहीं दे सकती पर तु एक इसरे को प्रमावित अवस्थ कर सकती है तथा एक इसरे को जुसलाकर या सममान्द्रमार्कर सौदेवाजी कर सकती है। सामा यत इस प्रणाली म केंद्रीय एव स्थानीय सरकारों है। स्वान प्रणाली म केंद्रीय एव स्थानीय सरकारों है। काई भी शासन विधिक हिन्द से एक इसरे के अधीन नहीं होता। सविधान के अत्तर्गत वोना स्तरों की सरकारों के मध्य प्रथम वार उनके कार्यों का विधिक विभाजन होता है। कार्य प्रथम वार उनके कार्यों का विधिक विभाजन होता है। तत्वश्चात राजनीतिक विध्व से विथाओं के विभाजन की आवश्यकता पत्रने पर विभाजन किया जाता है। यदि जरूरत पड़े तो यायपालिका को भी इस कार्य में सप्तर्व कर लिया जाता है। इस व्यवस्था स दोनो प्रकार की मरकारा का एक इसरे पर निमर रहना प्रमुख महत्व की बात है जिसस कि निणय शक्ति कही कियी एक सरकार डार हस्तर न करनी जाय। "-"

जपयनत परिभाषा म सधीय शासन की दो जुन्याँ (twin) विनेपताओं अवात
धासना की अपने अपन क्षेत्र म स्वतात्रता एवं के द्रीय तथा स्थानीय सरकारों है।
परस्पर तिमरसा (independence and inter dependence of the central and
local governments) का उल्लेख किया गया है। तथवाद का भी विकास हो रही
है। प्रारम्भ म राज्या (सथ की घटक इकाइयो) भी स्वतात्रता पर अधिक वन विवो
गया था। इस व्यवस्था को Dual Federalism कहा जाता था। 20वी सबी मैं
विभिन्न धासना म परस्पर सहयोग भी प्रवत्ति का अधिन विकास हुआ है। अस सपवाद
का भी स्वरूप सहयोगी (cooperative) हो गया है। इस Cooperative Federalism
भी सना दो गयी। विले भी उपरोक्त परिमापा हथ सपवाद (Dual Federalism)
धा सहयागी सपवाद (Cooperative Federalism) तक के विकास को स्थिति की
स्थान गरती है। या विल भी परिमापा था होयरे तथा अप विज्ञान की परिमापा
धा सहयोगी सपवाद (टेंग की परिमापा था होयरे तथा अप विज्ञान की परिमापा
धा सही अधिक नमनीय है और आधुनिक सपवाद की विद्यायां । अधिम मती

²³ Vile The Structure of American Federalism, 1961, p 199

प्रकार ब्यक्त करती है। स्वय द्वीयरे ने प्रो विले के तकों को स्वीकार किया है। 24 संघीय शासन में एकता (unity) एवं वैविष्य (diversity) के लामों का समावय सम्मव हुआ है।

सघवाद की मुख्य विशेषताएँ निम्नवत् है

- (1) सचीय राज्य का सविधान सर्वोच्च तथा लिखित एव कठोर होता है।
- (2) के द्वीय सरकार एव प्राचीय या राज्या की सरकारों में शासन की शक्ति का विमाजन होता है। भै
- (3) एक निष्पक्ष यायालय होता है जो के द्वीय एव राज्या की व्यवस्था-पिकाजा की विधिया एव झासनो के कार्यों को सविधान विरोधी होने पर अवैधानिक धोपित कर सके एव के द्र तथा राज्यों या दो राज्यों के मध्य विवादा मे अत्तिम निष्पय दे सके । प्राय हर सधीय शासन में सर्वोंच्च यायालय या सधीय यायालय होता है जिसे सिविधान के सरक्षक की सज्ञा दो जातो है और जिसे के द्र एव राज्या के विवादों के सम्बाध में मौतिक क्षेत्राधिकार होते हैं।

सघात्मक राज्य मे के द्वीय श्वासन एव के नीय या घटक इकाइयो की सरकारों में शक्तियों का विमाजन होता है। जत एक ऐसी सत्ता की आवश्यकता होती है जो शासन की शासियों के विमाजन को निष्वित एव निषारित कर रुके। यह सत्ता स्वय सिवधान है। अत सधीय राज्य में सविधान सर्वोच्च होता है जिससे दोनों सत्ताओं में क्षेत्र सम्बंधी कोई विवाद उत्पन्न हो सके। अत स्पष्ट शक्ते में धक्ति विमाजन अपेसित है। इसके अतिरिक्त सविधान की व्यार्था करने और सधीय एव राज्यों की सरकारों या विमिन्न राज्यों की सरकारों के मध्य उत्पन्न विवाद या विवादा का निणय करने के लिए एक सर्वोच्च यायालय की आवश्यकता होती है। सयीय सविधान विस्तित एव कठोर होते है। उनकी सशोधन प्रणाती कठोर होती है अर्थात् सामा य विधिन्न स्वार्थ के मध्य शक्तिया जा सकता। विधिन्न के के द्वीय सार्थ सोनीय सार्थ सोनीय सार्थ सार्य शक्तिया के सम्प्य शक्तिया के विमाजन म परिवतन के लिए विद्यंच व्यवस्था होती है। अत सधीय मविधान म सशोधन प्रणाती का स्पष्ट उत्लेख वाद्य नीय है। जो राज्य उपयुक्त विशेषताओं को पूण नहीं करते उन्ह सधीय राज्य नहीं कहा

²⁴ Wheare K C Federal Government, Footnote 2, p 14

²⁵ संपीय राज्य की घटक इकाइयों ने लिए 'राज्य' शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये पटक इकाइयों पूरे जयों में राज्य नहीं हैं फिर भी जय उचित शब्दावली के जमात म इनके लिए 'राज्य' "बद का ही प्रयोग किया जाता है। द्वीयर ने सम (federation) को ने द्वीय सरकार के लिए 'General Government' शब्द ना प्रयोग किया है एव राज्या या प्रान्तीय सरकार के लिए regional यानी क्षेत्रीय सरकार शब्द का प्रयोग किया है। तुख बिद्धान स्पारमक राज्य के केन्द्रीय सासन के लिए 'Federal Government' शब्द का प्रयोग करते हैं। समुक्त राज्य अमेरिका स ने 'द्वीय शासन को फेडरल यननमण्ट रहा जाता है। समुक्त राज्य अमेरिका स ने 'द्वीय शासन को फेडरल यननमण्ट रहा जाता है।

देने वा प्रयत्न किया है। प्रो विले न 1789 ई म अमेरिकी सधीय ध्वस्ता में नायप्रणाली का अध्ययन व्यावहारिक हृष्टि से तिया है। वे इस अप्रयत्न म प्रो ए एव विल (Prof A H Brich) ने विचारा स सहस्त हैं। विल के अनुसार अप अस क्षेत्र म स्वत म होते हुए भी सधीय राज्या की के न्रीय एव राज्या की सरकार पर तरस सहयोग को अधिकाधिक प्रवत्ति पायी जाती है। अत विल सधारमक शासन या राज्य किसी ऐसी परिभाषा को स्वीनार नहीं करते हैं जिसम कंद्रीय एव राज्या ने सरकार की अपने-अपने क्षेत्र में क्षेत्र करते वा पर वल दिया गया हो। प्रो विल सम किदी एक अनिवाय निक्का पत्र के नीय सरकारों म सहयोग को अवस्था को सधवाद की एक अनिवाय विष्ठका मानते है। एम के सी विले ने सथवाद की निम्नतिविद्यत परिनापा शो है

'संपवाद शासन की वह प्रणाली है जिसम क्षेत्रीय सत्ताएँ पारस्परिक रूप वे निमर राजनीतिक सम्ब घा म आवढ हाती हैं। इस प्रणाली म एसा सत्तुन्त एवा जाता है कि कोई भी सरकार एक दूसरे को आदेश नहीं दे सकती पर तु एक दूसरे को प्रमावित अवस्य कर सकती है तथा एक दूसरे का फुमलाकर या सममानुकार गीरेवाओं कर सकती है। सामा यत इस प्रणाली म केंद्रीय एव स्थानीय सरकार पे स्वाप्त कर पाय सममानुकार स्वत न एक यायिक अन होता है लेकिन यह व्यवस्था अनिवाय नहीं है। कोई भी शासन विधिक इंग्टि से एक दूसरे के अधीन नहीं होता। सविधान क अन्तगत दोना स्तरो के सच्य प्रथम बार उनके कार्यों का विधिक विमाजन होता है। साम विधक होट से विपया के विमाजन की आवश्यकता पड़ने पर विमाजन किया जाता है। यदि जरूरत वर्षे तो यायपासिका को भी इस काम मे समुक्त कर लिया जाता है। इस व्यवस्था म दोना प्रकार की सरकारों का एक दूसरे पर निमर रहा। प्रमुख महत्व की बात है जिससे कि निषय शक्ति कही किसी एक सरकार इंग्रं इस्तगत न करली जाय।' "

उपर्यक्त परिमाया म सधीय शासन की दो जुड़कों (twin) विशेषताओं अर्था होसनों की अपने अपन क्षेत्र में स्वतन्त्रता एवं के द्रीय तथा स्थानीय सरकारा है रस्तर तिमारता (independence and inter-dependence of the central and local governments) का उल्लेख किया गया है। सचवाद का भी विकास हो हो है। त्रारम्म म राज्या (सम की घटक इकाइया) की स्वतन्त्रता पर अधिक वल दिया गया था। इस व्यवस्था का Dual Federalism कहा जाता था। 20थी सदी म विनिन्न शासनों म परस्पर सहयोग की प्रवत्ति का अधिक विकास हुआ है। अत सचवार का भी स्वरूप सहयोगी (cooperative) हो गया है। इस Cooperative Federalism भी सहयोगी सचवाद (Cooperative Federalism) तक के विकास की स्थित की उपरोक्त परिमाया द्रीय सचवाद (Dual Federalism) तक के विकास की रिवर्त की उपरोक्त परिमाया भी ह्रीयरे तथा अथ विद्वाना की परिमायाओं से कही अधिक नमनीय है और आधुनिक सचवाद की विश्वेषताओं को अधिक मनी

प्रकार व्यक्त करती है। स्वय ह्वीयरे ने प्रो विले के तर्कों को स्वीकार किया है।²⁴ सघीय शासन में एकता (unity) एव वैविघ्य (diversity) के लामो का समन्वय सम्मव हुआ है।

सघवाद की मुख्य विशेषताएँ निम्नवत है

- (1) सधीय राज्य का सिवधान सर्वोच्च तथा लिखित एव कठोर होता है।
- (2) के द्रीय सरकार एव प्रात्तीय या राज्यां की सरकारां में शासन की शक्ति का विमाजन होता है !**
- (3) एक निष्पक्ष 'यावालय होता है जो के द्रीय एव राज्यों की व्यवस्था-पिकाओं की विधिया एव शासनों के कार्यों को सविधान विरोधी होने पर अवैधानिक भीषित कर सके एव केंद्र तथा राज्या या दो राज्यों के मध्य विवादा में अन्तिम निष्पय दे सके। प्राय हुर संधीय शासन में सर्वोच्च 'यावालय या संधीय 'यायालय होता है जिसे सिविधान के सरक्षक की सज्ञा दो जाती है और जिसे केंद्र एव राज्यों के विवादों के सम्बाध में मौलिक क्षेत्राधिकार होते हैं।

सघात्मक राज्य में के द्वीय शासन एव क्षेत्रीय या घटक इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विमाजन होता है। अत एक ऐसी सत्ता की आवश्यकता होती है जो शासन की शास्त्रियों के विमाजन को निश्चित एव निषरित कर सके। यह चता स्वय सिवधान है। अत सभीय राज्य में सविधान सर्वें ह्वां होता है जो सासन की शास्त्रियों है। अत सभीय राज्य में सविधान सर्वें च्व होता है निससे दोनों सत्ताओं में सेत सम्बंधी कोई विवाद उत्पन्न न हो सके। अत स्थट शब्दा में चित्त विमाजन अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त सविधान की व्यारण करने और सभीय एव राज्या की सरकारों के मध्य उत्पत्र विवाद या विवादों का निणय करने के लिए एक सर्वोच्च यायालय की आवश्यकता होती है। सभीय सविधान निस्तित एव कठोर होते हैं। उनकी सशोधन प्रणाती कठोर होती है अपातृ सामा य विधि-प्रतिया द्वार सविधान में किश्चय आपाती को स्था जा सकता। यविधान में के द्वीय सांक्षीय सरकारों के मध्य शतियों के विभाजन म परिवतन के लिए वियोव व्यवस्था होती है। अत सभीय सविधान म सदीवन प्रणाती का स्थय् उत्विच वाह्य नीय है। जो राज्य उपर्युक्त विशेषताओं को पूण नहीं करते उन्हें सभीय राज्य नहीं कहा

²⁴ Wheare, K C Federal Government, Footnote 2, p 14

²⁵ सपीय राज्य की घटक इकाइयो ने लिए 'राज्य' शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये घटक इकाइया पूरे अवों म राज्य नहीं हैं फिर भी जय उचित शब्दायली के अमान म इनके लिए 'राज्य' "गब्द का ही प्रयोग किया जाता है। ह्वीयर ने सथ (federation) की केन्द्रीय सरकार के लिए 'General Government' राब्द का प्रयोग किया है एव राज्यों या प्रातीय सरकार के लिए regional यानी राब्द का प्रयोग किया है। कुछ विद्वान स्पारमक राज्य के मेन्द्रीय सासन के लिए 'Federal Government' शब्द का प्रयाग नरात है। समुक्त राज्य अमरिका प्रयोग किया है। सुक्त विद्वान स्पारमक राज्य के मेन्द्रीय सासन के लिए 'Federal Government' शब्द का प्रयाग नरात है। सपुक्त राज्य अमरिका म केन्द्रीय सासन को फुंडरल गवनमण्ड महा जाता है।

जा सकता । ऐसे राज्य को अद्ध सधीय राज्य (Quasi Federal State) की सजी दी जाती है ।

सघ शासन के गुण

(1) सधीय राज्य के रूप म छोटे एव कमजोर राज्यों को सगिठत होकर दाक्तिशाली राज्य वनने का अवसर प्राप्त होता है। सधीय राज्य के अतगढ छोटे राज्या की स्वतात्रता एव पृथक अस्तित्व अक्षुण्य वने रहते हैं तथा उन्हें सुरक्षा एवं आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त अवसर भी प्राप्त होता है।

(2) मापा, घम, जाति, वर्ग आदि की विभिन्नताओं वाले देशों के लिए सप्र शासन विशेष रूप से उपयोगी हैं। इनमं विभिन्नताओं की रक्षा होते हुए एकता स्वा पित की जा सकती है। के ब्रक्टत एवं विकेट्रित शक्तियों में सन्तुलन स्वापित हा सहता है। संघीय शासन के अन्तरात राष्ट्रीय एकता एवं स्थानीय शासन दोना के ही लाग सम्मव होते है। मारत जैसे देख में जहां भारतीयता तथा भाषायी एवं धार्मिक विभिन्न ताएँ पायी जाती है, संघारमक शासन-पद्धति ही खेण्डतम एवं अमुकूल पद्धति है।

(3) विशाल देता के लिए एकात्मक शासन की अपेक्षा समात्मक शासन अपिक उपयुक्त है। प्रशासनिक क्षमता की हप्टि से भी विशास देशा म समीय धानन ही श्रेण्ठ है। एकात्मक क्षासन के अत्यात विशास देशा की व्यवस्था मसी मीति नहीं चल सकती। इसके विषयो, सभीय प्रणाली के अत्यात अखिल देशीय महत्व के विषय के स्त्रीय शासन ने एव शेष विषय स्थानीय सरकारों के अभीन होते हैं। कतत्वस्थ स्थानीय शासन को एव शेष विषय स्थानीय सरकारों के अभीन होते हैं। कतत्वस्थ स्थानीय आतता का शासन-काय से सम्बन्धित होने के कारण सावजनिक शिक्षा प्राप्त होती है और जनम शासन ने प्रति देश भी उत्यन होती है।

(4) लॉड ब्राइस के अनुनार सधीय शासन म जनता के अधिकारा के अति क्ष्मण की अपेक्षाकृत कम सम्यावना होती है । लाड एक्टन के अनुसार लोकत न म शासन की निरकुश्वता पर जो निय नण लगाय जाते हैं, उनमे सर्वाधिक महत्वपूण एक

एकमात्र अयुरा सघ शासन प्रणाली ही है।

(5) सपीय शासन म सावजनिक जीवन म विभिन्न प्रकार के अपीत एवं नीतिक, सामाजिक एवं आधिक प्रयोगों के सिए सुगमतापूर्वक अवसर प्राप्त हाते हैं। सप पी इकाइया के शामन अपने क्षेत्रों म मिन प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं और यदि जनम जह सफलता प्राप्त होती है तो अप राज्या हारा भी उसका अनुगमन किया जा मचता है। इसने विषयति, यदि विसी राज्य म कोई नीति असफल होती है ता उसवा दुष्प्रमाय दूसरे राज्या पर नहीं पटता।

याइस वे अनुमार सथ शासन व निम्नलिखित गुण हैं

(1) राष्ट्रीय राज्य क जन्तगत छोटे राज्या को अपने अस्तित्व को बनाय रागना मध्मव होता है।

²⁶ Bryce The American Government, Ch 29 30

- (2) देश की उत्रति शीध्रता एव सुचार रूप म सम्भव होती है।
- (3) नागरिका की स्वतन्त्रता की अधिक सम्मावना होती है और केद्रीय गासन की निरक्षतता में वृद्धि नहीं हो पाती है।
 - (4) शासन सम्बंधी नवीन प्रयोग सम्भव होते है।
- (5) सपीय शासन देश के विस्तार एव विभिन्नता-जनित दोषों से उत्पन्न खतरों को कम करता है।
 - (6) के द्वीय व्यवस्थापिका का कायभार कम हो जाता है।
 - (7) जनता को राजनीतिक शिक्षा एव प्रशिक्षण मिलता है।
 - (8) स्थानीय शासन में भी जनता सिक्य भाग लेती है।

फाइनर⁸⁷ ने निम्नलिखित शब्दों में सथ शासन के गुणों का उल्लेख किया है

- (1) सघ राज्य मे प्रयोग के अनेक अवसर होते है।
- (2) नवीन प्रयोगा के दुष्परिणाम एक क्षेत्र तक सीमित रहते है तथा सफलता का लाग्न सभी वैशो को प्राप्त होता है।
 - (3) शासन को स्थानीय समस्याओं का ज्ञान रहता है।
- (4) दिन-प्रतिदिन के शासन काय मे जनता की दिन रहती है और वे उसकी कठिनाइया को दूर करने के लिए शासन पर दबाव डाल सकते हैं।

सघ शासन के दोए

- (1) सथ शासन में बिधि, प्रश्नासकीय सगठन एव काय-पद्धित की विभिन्नता पायी जाती है। के द्रीय एव अनक स्थानीय राज्यों की पृथव पृथक विधिया होती है। साधारण नागरिका को इससे वड़ी काठनाई होती है और उनके समक्ष अनेक उसन्ने आती हैं। अर राज्यों व्यापार सन्वची समस्याएँ मी उत्पन्न होती है। अनेक ऐस विध्य होते हैं जो सामा य महत्व के होते हैं लेकिन राज्या की शक्ति के अत्वगत होने के कारण प्रत्येक राज्य द्वारा अपने क्षेत्र के लिए अल्य-अल्य नियम बनाये जाते हैं।
 - (2) राष्ट्रीय सरकार एव राज्यों की सरकारों म क्षेत्राधिकार सम्बंबी विवाद उत्पत्र हो जाते है।
 - (3) सघीय राज्य में दोहरी शासन प्रणाली के कारण प्रशासन अत्यिक व्ययसाच्य होता है। सघ में सेवाओ (services) का दहरा होना भी स्वामाविक है।
- (4) सधीय खासन की विवेश नीति शक्तिशाली नहीं होती है इस तक में बहुत अधिक बल नहीं है। समुक्त राज्य अमेरिका की विवेश नीति को कमजोर नहीं कहा जायेगा। लेकिन सप की इकाइया के द्वीय शासन द्वारा की गयी स्विथों के पालन के सम्बाध में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं जिसके कारण ने द्वाको द्विधा-

²⁷ Finer, H op cut, p 184

पूण स्थिति का सामना करना पडता है। उदाहरण के लिए, सयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने जापान को यह जास्वासन दिया था कि अमेरिका मे जापानियों के साथ नोई भेदमाव नहीं किया जायेगा। लेकिन केलीफोर्निया राज्य ने जापानिया के सम्वधन विभेदकारी नियमो का निर्माण कर दिया था। इस प्रकार की कठिनाई की मारत मे उत्पत्र होने की कम सम्मावना है क्योंकि केंद्र द्वारा सम्पादित सिंध्यों विरोधी राज्य की विधि निष्प्रमावी होती है।

(5) सघ शासन के सविधान लिखित होते है अत अपेक्षाकृत उनम सरनता

से सशोधन सम्भव नही होते ।

(6) सप ज्ञासन के सबसे बड़े दो दोप है—प्रथम, असन्तुष्ट राज्य सघ से पृष्क होने का प्रयत्न करने है। उदाहरण के लिए, सयुक्त राज्य अमेरिका म दासता के प्रश को लेकर दक्षिणी रियासतो ने सच से पुषक होने की धमकी दी थी और अमेरिनी गृह-युद्ध का सूत्रपात हुआ था। इस युद्ध मे विद्रोही दक्षिणी रियासर्ते पराजित हुई पी और अमेरिका की एकता की रक्षा हो सकी थी। इस प्रकार की पृथकत्ववादी प्रवर्ति ^{हव} द्मासर को कमजोर करती है। भारत में भी विघटनकारी तत्व सिक्रम है। प्रातीका और स्थानीयता की तीव्र मावना के कारण तमिलनाडु के द्रविण मुन्नेत्र कडगम नाम । राजनीतिक दल ने स्वतान राज्य की माग की है। नागा विद्रोही भी नागालण्ड ने स्वतान राज्य बनाना चाहते हैं। सघ राज्यों म विघटनकारी प्रविति का पन्पना स्यामाविक एव सरल होता है। हर प्रदेश की जनता की सास्कृतिक एकता को अपन प्रदेश के राजनीतिक सगठन से सहज ही सहायता एव प्रेरणा प्राप्त हो जाती है। सप राज्या का दूसरा दोष यह है कि कुछ प्रभावनाली राज्य अपना गुढ बनाहर सम्पूण सप पर हावी होने एव अपने हिता के सवधन के लिए प्रत्येक सम्मद प्रयत करत रहत हैं।

(7) लीकॉक के अनुसार सथ शासन राजनीतिक एव बाह्य मामली न शर्ति घाली और जातरिक एव आर्थिक मामलो म कमजोर प्रमाणित हुआ है। हा आर्धी यादम इस आलोचना को समुक्त राज्य अमेरिका को हृष्टि म रखकर अस्वीकार कर्ते हैं। सपुक्त राज्य अमेरिका का सथ आतरिक एव बाह्य, राजनीतिक एव आर्थिक,

दाना ही दृष्टिया स शनितशाली राष्ट्र प्रमाणित हुना है।

(8) बायसी के जनुसार सथ शासन कमजोर एव अनुदारवादी होता है और उनम विधि की प्रधानता होती है। 12 संघीय शासन की कमजोरी का कारण दो समान सत्तात्रा व मध्य राजनीतिक शक्ति का विमाजन है। इसके अतिरिक्त, अवराप एव स पुरा की पद्धति (जिसके द्वारा शासन का एक अब दूसरे अस की गावित को निव ितत गरता ?) व गारण अनावश्यक धनित ना विनान होता है। संघीय सर्वियान र कटार हान क कारण उसम शाध्यतापूर्वक परिवतन भी सम्भव नहीं हो पात !

²⁸ Dicey The Law of the Constitution 1959, sec 171-180

जनता सभीय सविधान के उपव घो को पवित्र एव अनुलपनीय सममने लगती है। इससे जनता म अनुदारवादो भावना का विकास होता है। उदाहरण के लिए, डायसी के अनुसार अवेरिको सीनेट को समाप्त करना लांड समा की तुलना मे कही अधिक कठिन पिछ होगा। अत सम राज्य मे राष्ट्रीय अनुदारवाद एव अनुदारवादी प्रवृत्तियों को और अधिक बढावा मिलता है सधीय सविधान मे यायपालिका की प्रमुखता होती है। जनता मे विधिक हण्टिकोण की विद्व हो जाती है। सधीय सवधानिक ह्यवस्था मे यायपालिका की हिपति विधि निर्माण करने वाले अधीनस्थ सवस् जैती है। कार्यपालिका की हिपति विधि निर्माण करने वाले अधीनस्थ सवस जैती होती है। कार्यपालिका की शक्ति सविधान द्वारा सीमित होती है एव यायाधीशा द्वारा सविधान की व्याख्या की जाती है। अत डायसी का मत है कि सववाद उन देशा म ही सफल हो सकता है जहां विधि के प्रति अधिकाहत अधिक श्रदा होती है और विधिक मावना का आदर किया जाती है।

हरमन फाइनर²⁹ के अनुसार सघवाद की मूख्य कठिनाइया निम्नलिखित हैं

(1) सप ज्ञासन दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था के कारण आधिक हर्ष्ट से खर्चीनी व्यवस्था है। इसम समय एव चिक्त पर्यास्तत कम होती है। उपयुक्त प्रशा सिनिक एव विधिक एकता तथा उसकी उपलिध के लिए बाफी समय पारस्परिक वार्ती म ही व्यतित हो जाता है। यातायात, स्वास्थ्य, रोजवार आदि की अनेक ऐसी समस्याएँ हैं जिनका सक्षमतापूषक प्रशासन अनेक प्रकार के अधिकारियों के अस्तित्व के कारण कठिन होता है।

(2) सविधान में सशोधन कठिनता से ही हो पाते है।

(3) जनता को सधीय धासन में अनेक उलक्षनों का सामना करना पडता है। व्यक्तिगत अधिकारा एवं वामित्वों सम्बन्धी मामलों में अपेक्षाकृत अस्पष्टता रहती है। किस सत्ता के क्या अधिकार हैं, यह विवाद का विषय होते हैं। अत सधीय राज्य में केंद्र एवं राज्या में क्षेत्राधिकार को लेकर अनेक विवाद उठा करते हैं।

(4) शासन से सम्ब धत अनेक काय ऐसे होते हैं जि ह सब शासन के अ त-गत पूण करना सम्मव नहीं होता । इसका कारण यह है कि सधीय शासन मे सांक्तियों का विमाजन विगत पीढिया की आवस्यकता एव परिस्थितियों की हिन्द से होता है । यतमान पीढी के आर्थिक एवं सामाजिक कतवां के सम्मादन के लए अपेक्षाकृत अधिक कें द्रीकरण की आवस्यकता होती है । शक्तियों के विमाजन के द्वारा इस वादनीय के द्री-करण का अमान होता है । सब शासन सत्ता के के ट्रीकरण का निषेध करता है ।

सघवाद का इतिहास

सघवाद आधृनिक युग में राजनीतिक सस्था के रूप में एक नवीन प्रयोग है। सघवाद सिद्धा त एव व्यावहारिक रूप में 1787 ई म अमेरिकी सघीय व्यवस्था के आरम्भ के साय प्रारम्म होता है। लेकिन सधीय शासन का विचार अत्यन्त प्राचीन

²⁹ Finer, H op cit, pp 184 85

है। प्राचीन भारत में राज्यो एव गणराज्या के सध थ। प्राचीन यूनान मं भी राज्या के सघ थे। सवप्रथम यूनान के 12 राज्यों ने पारस्परिक सुरक्षा की हिन्द स एकीवन सघ (Achean League) की स्थापना की थी लेकिन 3 से 2 सदी ई पू यूनानी नगर राज्यों के इस सघ मं अनेक संशोधन एवं परिवद्धन करन पढ़े थे। कोरिय, मगारा एव दक्षिणी यूनान के कई नगर-राज्य इसमे सम्मिलित हो गये थे। विदेश नीति एव सुरक्षा सम्ब भी सभी मामले राज्या द्वारा लीग को समिपत कर दिय गये वे और आन्तरिक मामला मे व पूण स्वतात्र वने रहे। यदि रोमन साम्राज्य का उदय न हुआ होता तो सम्भवत यूनान के सभी नगर-राज्य इसके सदस्य वन गये होते।

मध्य-युग की 13वी एव 14वी सदी के इटली के नगर-राज्यों के राजनीतिक सगठना को सघ की सज्ञा प्रदान कर सकते हैं। 1291 ई में स्विस परिसव (Suis Confederation) का उदय हुआ या । यह सधीय शासन की दिशा से एक महत्व पूण कदम है। तीन के टनो-पूरी, स्वेज और अण्डरवेल्डन-न जो रोमन सम्राट के अधीन थे, पारस्परिक सुरक्षा के लिए अपने की एकता के सूत्र म बाध लिया था। काला तर मे इन तीनो के टना के संयुक्त राज्य ने विकास करते हुए स्विटजरलण्ड क

आधृनिक संघीय शासन का रूप धारण कर लिया है।

सयुक्त राज्य अमरिका म 1789 ई मे उसके नये सविधान के लागू होने पर यथाय रूप म सद्य शासन की व्यवस्था का विकास प्रारम्भ हुआ है। यद्यपि अमेरिकी सविधान-निर्माताओं ने यूनानी उदाहरण एवं अनुभव की बार-बार दहाई दी परन्तु व यह यली मौति जानते ये कि सधीय शासन-ध्यवस्था की वे प्रथम बार स्थापना कर रहे हैं। स्मरणीय है कि 1777 ई म स्थापित परिसंघ (Confederation) की व्यवस्था, 1789 ई म सविधान के निमाण एव उसके लागू होने पर आधुनिक स्पापी सधीय व्यवस्था मे परिणत हो गयी। 19वी सदी म अनेक सघ राज्या का उदय हुआ है। 1848 एव 1874 ई म स्विटजरलण्ड के सविधान को संशोधित करके आयुनिक रूप प्रदान किया गया है। 1837 एव 1867 ई में कनाडा म सप गासन मी स्थापना की गयी। 1867 ई म उत्तरी जमन सघ का निर्माण हुआ। 1871 ई म जमन साम्राज्य की स्वापना हुई। 1902 ई म आस्ट्रेलिया म सघ राज्य एवं 1905 इ मे दक्षिणी अफीका के सघ की स्थापना की गयी। दक्षिण अफीका के मही द्वीप म मनिसको एव ब्राजील म भी सब राज्य की स्वापना हुई । वतमान सदी म रूम, भारत, मलेशिया, वस्टइण्डीज, युगोस्लाविया एव इण्डानेशिया आदि देना र मधीय ग्रामन की स्थापना हुई है। सामा यत हस की व्यवस्था को सधीय ग्रामन की श्रेणां म नहीं रसत । परन्तु रूस का सविधान (1936) अपन दन को परिस्पिति^{दा} र जनुभार परिवर्तित संघीय व्यवस्था की स्थापना करता है।

सघ शासन के निर्माण में सहायक तत्व सध शामन को स्यापना एव मुहदूता म अग्रलिखित परिस्थितियाँ सङ्ग्यह हाती है

- (1) प्रथम आवस्यक्ता भौगोलिक सामीप्य की है। यदि सच का निर्माण करन वाले राज्य एक दूसरे स बहुत दूर स्थित है और एक दूसरे के प्रदेश से सयुक्त नहीं हैं ता डायसी के अनुसार संघ की स्थापना नहीं हो सकती अपर यदि हा जाती है ता उसका दीघकाल तक कायम रहना सन्देहजनक है। प्रारम्भ म पाकिस्तान भी सघ या। पूर्वी पानिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से हजारा मील दूर था। दोना म मापा, जाति, संस्कृति, हिता आदि से सम्बन्धित गहरे मतभेद थे। जन्त म पूर्वी बगाल की जनता न बगला देश के रूप म संगठित होकर प्रयक्त होने का आन्दोलन किया और स्वतात्र हो गयी।
- (2) सघ की घटक इकाइया अर्थात राज्यो को समान हाना चाहिए। यदि कोई राज्य अय इकाइया के मुकाबले म अधिक शक्तियाली एवं प्रभावशाली है तो रोप या अन्य राज्या पर उसके हानी होने का मय उत्पन हो जाता है। गिरुकाइस्ट के अनुसार "आदण सुघ के लिए राज्या म आकार एव शक्ति की दृष्टि से पुण समानता वाद्यनीय है।" श्राच्या मे पायी जाने वाली असमानताओं को वधानिक उपायी द्वारा चुनतम बनाया जा सकता है। इसका एक तरीका यह है कि व्यवस्थापिका के दितीय सदन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए । बायसी ने तो धन की द्रिप्ट से भी राज्या की समानता पर बल दिया है। 32 लेकिन घटक इकाइयों की पुण समानता प्राय सघ राज्या म देखने म नही आती है। उदाहरण के लिए अमेरिका के घटक राज्यों को विधिक हुप्टि से समानता प्राप्त है। आस्ट्रेलिया के घटक राज्या को भी उच्न सदन-सीनेट-म समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यद्यपि भारत मे उच्न सदन म राज्या को जनसंख्या के अनुपात पर प्रतिनिधित्व प्राप्त है फिर भी प्रत्येक सघ म विधिक हृष्टि से सभ की प्रत्येक इकाई का समान स्तर प्राप्त होना चाहिए ।
 - (3) भाषा, संस्कृति आदि की एकता भी सध शासन की सफलता में सहायक होती हैं। लेकिन ये अनिवास तस्व नहीं है जैसे कि भारत विभिन्न भाषा-मापिसा का सघ है। स्विटजरलैण्ड मे चार मापा-मापी जातिया निवास करती है। रूस मे भी मापा की विभिन्ता पायी जाती है।
 - (4) सप निर्माण के लिए दो विरोधी भावनाओं का होना आवश्यक है। सच में सम्मिलित होने वाले राज्या की जनता में एक तरफ मिलकर संघ बनाने की एकता की मावना होनी चाहिए तो दूसरी तरफ उनमे अपने स्वतात्र राजनीतिक अस्तित्व को वनाये रखने की तीच्र उत्कण्ठा भी होनी चाहिए। अत उनम जहा सथ (union) की मावना होनी चाहिए वहा एकता (unity) की मावना नही होनी चाहिए।
 - (5) सम की सफलता के लिए सम्बन्धित जनता म उच्च राजनीतिक चेतना का होना भी आवश्यक है। सधीय व्यवस्था अपक्षाकृत जटिल काय पद्धति है। सघ

³⁰ Dicey op est, pp 137 139
31 Gilchrist Principles of Political Science, p 377

³² Dicey op cat, p 139

राज्य मे दो शासन होते हैं-जनता इनके अधीन निवास करती है। अत याता के प्रति अपने दायित्वा एव दाक्तिया म समन्वय स्थापित करन की धमता बनता म होनी चाहिए ।

परिसध

परिसय (Confederation) सप्रमु राज्या का सघ है जा निश्वित स्वा की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। गानर के अनुसार "परिसम राज्या के कुछ माज सामान्य उद्देश्यो, विदीयकर समान बाह्य सुरक्षा के हुत निर्मित सथ है। "अ गेटेत ह अनुसार 'परिसध राज्यो का सघ ह । सामा य हिता वाले राज्य समानता के आधार पर एकत्रित हाकर एक के द्रीय शासन का निर्माण करते हैं और उसे कुछ शिंहण प्रदान करते हैं।"34 सो एफ स्ट्राग के अनुसार "परिसंघ अनेक राज्या का टाला ढाला सघ है जो राज्य नहीं होता है।"35

परिसम म सम्मिनित होने वाले सदस्य राज्य सप्रमु बने रहत हैं। परिनम ह सदस्य होने के कारण वे अपनो सप्रमुता का परित्या नहीं करते। परिसंघ के निमान से किसी नवीन राज्य का जाम नहीं होता और सदस्य राज्य विधिक दृष्टि से स्वरा होत हैं। के दीय ग्रासन के होत हुए भी के दीय सत्ता का निर्माण नहीं होता। कदाय शासन केवल सदस्य राज्या की शासा मात्र होता है। परिसम को सत्ता सत्स राज्यो द्वारा प्रदान की जाती है। अत उसकी सत्ता का आधार सदस्य राज्यों ही स्वीकृति है।

परिसय म सामान्यत एक के द्रीय विधानमण्डल या कारीस होती है। परिस् का निर्माण एवं केन्द्रीय धासन की धाक्तियां की ब्याख्या करने वाले प्रपत्र को सविधान कहत हैं। वास्तव म यह परिसंघ के सदस्य राज्या के मध्य एक समनीता या सिंध है। सदस्य देश परिसाय से अपनी इच्छानुसार प्रयक्त हो सकते हैं और सदस्यता का परित्याग अविधिक या अवैधानिक काय नहीं माना जाता है। परितम वस्तुत एक सरात समभौता है। एकारमक शासन की तुलना मे परिसय के सदस्य राज्य पूणत स्वतन्त्र होते हैं। उनकी अपनी सेना, सरकार एव पृथक सत्ता होती है। वे स्वतः रूप सं सिधयों कर सकते है। संपात्मक राज्य एवं परिसंघ ने अन्तर है। सम राज्य की सदस्यता एक बार प्रहण परने उसका परित्याम नहीं किया जा सकता और न परिसय की तरह सपीय राज्य की गटन इनाइया की प्रमुसता ही प्राप्त होती है।

-Garner of st, p 251
34 'Confederation is a form of association of States having interests in common (and they) unite on the basis of equality and set up, a central government to which are delegated certain powers -Gettell Political Suence, 1956, p 470

35 Strong, C. F ep cut , p 103

[&]quot;A confederation is a union or association of States formed for 33 the purpose of promoting or reducing certain specific objects specially the maintenance of their common external security."

और न वे पृथक वैदेशिक या सैनिक व्यवस्थाएँ ही कर सकते है। सामा यत परिसघ का अत एकात्मक अथवा सघात्मक राज्य म होता है। ³⁶

परिसप मे न तो नागरिक होते हैं और न ही प्रजाजन, जा उसकी आजाओ का पालन करें या जिनके अधिकार या कतव्य हो । जैलिनिक के अनुसार परिसप दो प्रकार के होते हैं एक जिनके नियमा का पालन सदस्य राज्यों की प्रजा नहीं करती है अपितु जिनका राज्यों से ही सम्ब घ होता है । इसरे वे जिनमें परिसप की कांग्रेस वास्तिक विधानमण्डल होता है और जिनके नियमों का पालन सदस्य राज्यों की प्रजा द्वारा किया जाता है। परिसप की कांग्रेस के सदस्य राज्यों की सरकारों की तरफ से मत देने हैं। परिसप की अपने नियमावि लागू करने की भी शक्ति प्राप्त नहीं होती है। परिसप की अपनी कोंग्रेस के स्वस्य राज्यों की सरकारों की नहीं होती है। परिसप की अपनी कोंग्रेस के स्वस्य राज्यों की सरकारों नहीं होती है। परिसप की अपनी कोंग्रेस कांग्रेस के स्वस्य राज्यों की सरकारी नीतियों पर ही निमर रहना पडता है।

परिसप की विधिक स्थिति के सम्बान में विद्वानों में मतभेद हें। जैलिनिक, बान मोहाल, बोरल एक बोपेनहाइम परिसध को राज्य नहीं मानते। उसे वे केवल एक सब मानते हैं। इसको न तो कोई विधिक ज्यक्तित्व प्राप्त हैं और न कोई क्षिकार और क्षमता ही प्राप्त हैं। दूसरे विद्वान जैस लीकर (LeFur), डीलोतर (DeLouter) एव सूल्ज (Schultz) उसे राज्य नहीं मानते परन्तु परिसध को जतर-राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्रदान करते हैं।

परिसंघ का इतिहास बहुत पुराना है। यूनानी काल में अनेक परिसंघ थे, जैसे—एिक्सन, लाईसियन, डीलियन लीग। मध्य-काल में रेनिस (Rhenish) परिसंघ (1254 1350), हैनिस्टिक लीग (Hanseatic League) (1367-1669), एव होली रोमन साम्राज्य (1526 1806) परिसंघ के उदाहरण है। परिसंघ के दा प्रेष्ठ वदाहरण समुक्त राज्य अमेरिका का परिसंघ (1781-1789) एवं जमन परिसंघ (1815-1867) हैं।

अमेरिकी परिसध केवल सदस्य राज्यों की मिनता का सघ था। सघ राज्य की अपनी कोई सममुता न थी। सदस्य राज्य पूर्ण स्वतः व बे और उन्होंने परिसध को अपनी कोई सममुता न थी। सदस्य राज्य पूर्ण स्वतः व बे और उन्होंने परिसध को अपनी सदा प्रदान नहीं की थी। वह केवल सामा य काल में "तुओ से रक्षा के लिए सध था। किसी सामा य प्रशासकीय एव यायिक जय का निर्माण नहीं किया गया । परिसध को कोंग्रेस के निर्णयों को किया वित करना सदस्य राज्या का ही काम था। कारिस का वहुत कम शक्ति प्रदान की भयी थी और कांग्रेस के पास अपनी विधियों को नियाचित करने के साथन नाममान के थे। फलत शासन की कमजोरी के फलस्वरूप उसका पतन हो गया।

³⁶ Asirvatham, E Political Theory, p 362

154 | आधुनिक शासनतात्र

समन परिसध³⁷ (1815-67 ई) मे विभिन्न आकार एव स्तर के 38 राज थे, जैस—राज्य, आण्ड डची एव स्वत न नगर। सदस्य राज्यों की स्वत का एव हवता तथा जमनी की बाह्य एव आतिरक सुरक्षा के लिए परिमय का निमान हुआ था। सदस्य राज्यों के प्रतिनिधिया की एक ससद (Diet) थी। डाइट को परि सप के नाम पर राजदूत भेजने, दूसरे देशा के राजदूतों का क्यानत करने, यु, ह पि एव विशेष परिस्थितिया म सदस्य राज्या के आतिरक मामला म हस्तक्षेप करने के अधिकार प्राप्त थे। प्रत्येक सदस्य राज्या के बिरेक्षा से सम्बन्ध स्थापित करने की स्वत कता थी। इस सम्बन्ध में केवल एक ही प्रतिव भ था। वह यह कि ऐसी किसी सिंध से परिसय की स्वत कता को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। युद्ध प्रारम्भ ही जाने की अवस्था म परिलय की ससद की स्थीकृति के बिना कोई सदस्य राज्य सींप नहीं कर सकता था। न एक सदस्य दूसरे के विषद्ध युद्ध की घोषणा ही कर सकता था। एक सामा या साम्राज्यीय न्यायालय या। इस यायालय के क्षेत्राधिकार सीनित थे। पर जुपरितय का अपना कोई प्रशासकीय प्रमाश के स्वापिकार सीनित थे। पर जुपरितय का अपना कोई प्रशासकीय प्रमाश वा । परित्य के निगय नियागिक करने का वायित्व सदस्य राज्या का था।

परिक्षप वा एक अन्य प्रयत्न 1907 ई मे यथ्य अमेरिकी राज्या—ावारे माता, कोस्टारीका हो इरास, निकारानुआ एव सालवेडर—ते किया था परन्तु इसका 1918 ई म अत हो गया।

उपयुक्त अय म कोई राज्य परिसम नहीं है। यह अल्पकालिक होते हैं। जो परिसम प्राचीन वाल म थे भी वे धीरे धीरे या तो एकारमक राज्य वन गय अपवी सपीय राज्य म परिणत हो गये। समुक्त राज्य अमेरिका का परिसम 1789 ई में सपीय राज्य म परिणत हो गया था।

संघवाद का व्यावहारिक स्वरूप FEDERALISM IN PRACTICE

प्रमुख संघीय देशों की संघीय व्यवस्था का विवरण इस अध्याय मे प्रस्तुत किया गया है ।

सयक्त राज्य अमेरिका की सघीय व्यवस्था

संयुक्त राज्य अमेरिका संभीय देश हैं और उसके सविधान का इतिहास संभीय शासन-व्यवस्था का इतिहास है। उत्तरी अमेरिका सं 17वी सदी के अन्त तक उपनिवेशों की स्थापना हो चुकी थी। इस क्षेत्र में अपना-अपना प्रमुख्न स्थापित करने के लिए कास और इंगलण्ड के मध्य संप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। इसमें अपेण विजयी हुए और वे उत्तरी अमेरिका के स्थामी वरे। 18वी सदी के मध्य तक 13 उपनिवेश स्थापित हो चुके थे। इन 13 उपनिवेशों ने इंगलेण्ड के विषद्ध अनेक कारणों से प्रेरिक स्थापित हो चुके थे। इन 13 उपनिवेशों की जनता न ब्रिटिका सरकार द्वारा नवीन कर लगाना। परिणामस्वरूप उपनिवेशों की जनता न ब्रिटिका ससद में प्रतिनिधित्व की मांग की। 'प्रतिनिधित्व के अमाव में कर नहीं' का नारा बुख्य हो उठा और युद्ध छिड़ यथा। 4 जुलाई, 1776 ई को 13 उपनिवेशों ने इंगलेण्ड तथा उसके सम्नाट के विषद स्वत नता की घोषणा (Declaration of Independence) कर दी। 15 नवस्बर, 1777 ई को इन 13 उपनिवेशों ने मिलकर एक परिसंध (Confederation) की स्थापना की। स्मरणीय है कि परिसंध के निर्माण की प्रेरणा का मूल कारण उपनिवेशों नी सुरुप की मांगना थी। इस समय सभी उपनिवेश पूण स्वतः न राज्य व और वे शासन के अधिकार नथीं सत्ता को सीपने के इन्हक नहीं थे।

परिसध के सिवधान को Articles of Confederation की सज़ा दी गयी। इसम कवल 13 धाराए थी। परिसध का नाम संयुक्त राज्य अमरिका राजा गया (प्रथम धारा)। परिसध का सदस्य बनने के परचात भी प्रत्येक राज्य अपनी सत्ता एव

¹ अमेरिकी स्वतानता का यह युद्ध 19 अक्ट्बर, 1781 ई तक चलता रहा और इस वप ग्रेट ग्रिटेन ने समुक्त राज्य अमेरिका की स्वतानता को स्वीकार किया। 1783 इ. में परिस सिंघ द्वारा इसको मायता दी गयी।

154 | आधुनिक शासनत त्र

जमन परिसध³⁷ (1815-67 ई) म विभिन्न आकार एव स्तर के 38 गर्स थे, जैसे—राज्य, ग्राण्ड डची एव स्वतान नगर। सदस्य राज्यों में स्वतंत्र एवं हवता तथा जमनी की वाह्य एवं आतरिक युरक्षा के लिए पित्रध का निर्मेष हुना था। सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियां की एक ससद (Diet) थी। बाइट नो भी सब के नाम पर राजदूत नेजने, दूवरे देशों के राजदूता का स्वागत करने, युढ, शीं व विशेष परिस्थितिया म सदस्य राज्यों के बातरिक मामला म हस्तक्षप करते हैं अधिकार प्राप्त थे। प्रत्येक सदस्य राज्यों के बातरिक मामला म हस्तक्षप करते हैं स्वतात्रता थी। इस सम्बाध में केवल एक ही प्रतिवध था। वह यह कि ऐसी कि सिंध से परिस्थ की स्वत नता को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। युढ प्राप्त हैं जो अवस्था में परिस्थ की ससद की स्विकृति के बिना कोई सदस्य राज्य शीं की अवस्था में परिस्थ की ससद की स्वीकृति के बिना कोई सदस्य राज्य शीं एक सामाय साम्राज्यीय यावालय था। इस यायालय के क्षेत्राधिकार सीनित थे। पर तुपरिसय का अपना काई प्रशासकीय या न ही था। परिसव के निण्य क्रियाँ करते का वायित्व सदस्य राज्यां का या।

परिसय का एक अप प्रयक्त 1907 ई में मध्य अमेरिकी राज्या—वार्ट माला, कोस्टारीका, हो डूरास, निकारागुजा एव सालवेडर—ने किया था परन् इसका 1918 ई मं अन्त हो गया।

जपर्युक्त अब में कोई राज्य परिसध नहीं हैं। यह अल्पकालिक होते हैं। वे परिसध प्राचीन काल में थे भी वे धीरे धीरे या तो एकारमक राज्य बन गये अध्या संघीय राज्य में परिणत हो गये। संयुक्त राज्य अमरिका का परिसध 1789 ई में संघीय राज्य में परिणत हो गया था।

³⁷ इन जमन परिसध को German Bund कहत हैं। जमन सब्द Bund' की अप लाग है।

सघवाद का व्यावहारिक स्वरूप FEDERALISM IN PRACTICE

प्रमुख सधीय देशो की सघीय व्यवस्था का विवरण इस अध्याय मे प्रस्तुत किया गया है।

सयुक्त राज्य अमेरिका की सघीय व्यवस्था

समुक्त राज्य अमेरिका संपीय देश है और उसके मविधान का इतिहास संपीय शासन व्यवस्या का इतिहास है। उत्तरी अमेरिका से 17वी सदी के अन्त तक उपनिवेशों की स्थापना हो चुकी थी। इस क्षेत्र में अपना-अपना प्रमुख स्थापित करने के लिए फास और इगलेण्ड के मध्य सन्तवर्षीय युद्ध हुन्ता था। इसन अप्रेज विजयी हुए और वे उत्तरी अमेरिका के स्थामी बने। 18वी सती के मध्य तक 13 उपनिवेश स्थापित हो चुके थे। इन 13 उपनिवेशों न इगलण्ड के विश्व अनेक कारणों से प्रेरिक होक्त काति की थी। इनम प्रमुख कारण था विदिश्य सरकार द्वारा नवीन कर लगाना। परिणामस्वरूप उपनिवेशों की जनता न ब्रिटिश सरकार द्वारा नवीन कर लगाना। परिणामस्वरूप उपनिवेशों की जनता न ब्रिटिश सरकार द्वारा नवीन कर सगाना। परिणामस्वरूप उपनिवेशों की जनता न ब्रिटिश सरकार द्वारा नवीन कर सगाना। परिणामस्वरूप उपनिवेशों की जनता न ब्रिटिश ससद में प्रतिनिधित्व की भाग की। 'प्रतिनिधित्व के अभाव में कर नहीं का नारा बुलन्द हो उठा और युद्ध दिइ गया। 4 जुलाई, 1776 ई को 13 उपनिवेशों ने इगलण्ड तथा उसके सम्राट के विद्ध स्वत नता की घोषणा (Declaration of Independence) कर दी। 15 नवम्बर, 1777 ई को इन 13 उपनिवेशों ने मिलकर एक परिसाय की प्रणा का मूल कारण उपनिवेशों की सुरक्षा की। समरणीय ह कि परिसाय के निर्माण की प्ररणा का मूल कारण उपनिवेशों की सुरक्षा की भावना थी। इस समय सभी उपनिवेश पूण स्वत न राज्य य और वे तीसन के अधिकार नयी सत्ता का सीण के इच्छक नहीं थे।

परिसप के सिवधान को Articles of Confederation नी सज्जा दी गयी। इसम केवल 13 धाराए थी। परिसध का नाम सयुनत राज्य अमरिका रत्ना गया (प्रयम धारा)। परिसध का सरस्य वनने के पश्चात भी प्रत्येक राज्य अपनी सत्ता एव

अभिरिकी स्वतात्रता का यह युद्ध 19 अक्ट्बर, 1781 ई तक चलता रहा और इस वप ग्रेट ग्रिटेन ने समुन्त राज्य अमेरिका की स्वत जता का स्वीकार किया। 1783 ई म परिस सिंध द्वारा इसको माण्यता दी गयी।

जमन परिसव³⁷ (1815 67 ई) म विमिन्न कानार एव स्तर के 38 राज्य थे, जैस—राज्य, बाण्ड डची एव स्वतान नगर। सदस्य राज्या की स्वतान नता एव इंडता तथा जमनी की वाद्या एव बातरिक मुरक्षा के लिए परिसव का निर्माण हुआ था। सदस्य राज्या के प्रतिनिधियों की एक मनद (Duct) थी। बाइट की परिसव का नाम पर राजदून भेजने, दूबरे देशों के राजदूतों का स्वायत करने, युद्ध, सिध एव विशेष परिस्थितिया में मदस्य राज्यों के आन्तरिक मामलों में स्टरलंध करने के अधिकार प्राप्त थे। प्रदेक सदस्य राज्य को विदेशों से सम्बाय स्थापित करने के अधिकार प्राप्त थे। प्रदेक सदस्य राज्य को विदेशों से सम्बाय स्थापित करने के स्वताना वी। इस सम्बाय में केवल एक ही प्रतिच था। वह यह कि ऐसी किसी सिंध से परिसय की स्वतानता को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। युद्ध प्रारम्म हो जाने की अवस्था में परिसथ की ससद की स्वीकृति के विना कोई सदस्य राज्य सिंध नहीं कर सकता था। न एक सदस्य दूसरे के विषद युद्ध की घाषणा ही कर सकता था। पर सामाय साम्राज्यीय प्यास्त्रय था। इस प्यायालय के क्षेत्राधिकार सीमित थे। परन्तु परिसाथ का अपना काई स्वासकीय यान नहीं या। परिसाथ के निजय कियानित करने का त्रास्त्र सदस्य राज्यों का या।

परिसय का एक अन्य प्रयत्न 1907 ई मे मध्य अमरिकी राज्या--- वाटे माना, कास्टारीका, हा कुरास, निकारागुका एव सालवंडर--- ने किया था पर तु इसका 1918 ई म अन हो गया।

उपर्युक्त अथ म काई राज्य परिसय नहीं है। यह अल्पकालिक होते हैं। जो परिसय प्राचीन काल में थे भी व घीर धीर या तो एकात्मर राज्य कन गय अयवा सपीय राज्य म परिजत हो गय। सञ्जूक राज्य अमरिका का परिसय 1789 ई म सपीय राज्य म परिजत हो गय। सञ्जूक राज्य अमरिका का परिसय 1789 ई म

³⁷ इस जमन परिसध ना German Bund नहत हैं। जमन शब्द 'Bund' ना जय लीय है।

सघवाद का व्यावहारिक स्वरूप FEDERALISM IN PRACTICE

प्रमुख सधीय देशो की सघीय व्यवस्था का विवरण इस अध्याय मे प्रस्तुत किया गया है।

सपुक्त राज्य अमेरिका को सधीय व्यवस्था

सपुक्त राज्य अमेरिका सधीय देश है और उसके सवियान का इतिहास सशीय शासन व्यवस्था का इतिहास है। उत्तरी अमेरिका मे 17वी सदी के अ त तक उपनिवेद्यों की स्थापना हो चुकी थी। इस क्षेत्र म अपना-अपना प्रमुख स्थापित करने के लिए फ़ास और इगलैण्ड के मध्य सप्तवर्धीय युद्ध हुआ था। इसमें अप्रेज विजयी हुए और वे उत्तरी अमेरिका के स्थामी बने। 18वी सदी के मध्य तक 13 उपनिवेद्य स्थापित हो चुके थे। इन 13 उपनिवेद्यों ने इगलण्ड के विकद्ध अनेक कारणों से प्रेरित होकर कारित की थी। इनमें प्रमुख कारण था विदिश्च सरकार द्वारा नवीन कर लगाना। परिणामस्वरूप उपनिवेद्यों की जनता न ब्रिटिश ससद म प्रतिनिधित्य की माग की। 'प्रतिनिधित्य के अभाव में कर नहीं का नारा चुल द हो उठा और युद्ध छिड़ गया। 4 जुलाई, 1776 ई को 13 उपनिवेद्यां ने इगलेण्ड तथा उसके सम्राट के विद्य स्वत तता की घोषणा (Declaration of Independence) कर दी। 15 नवस्यर, 1777 ई को इन 13 उपनिवेद्यां ने मिलकर एक परिस्तप (Confederation) की स्थापना की। स्मरणीय ह कि परिसंध के निमाण की प्रेरणा का मूल करण उपनिवेद्यां नी सुरना की मोनवा थी। इस समय सभी उपनिवेद्यां की सुरना की मोनवा थी। इस समय सभी उपनिवेद्यां के प्रतिवार पूप स्वतन्य राज्य थे और वे सासन के अधिकार नयी सत्ता का सोपने के इज्दुक नहीं थे।

परिसध के सिवधान को Articles of Confederation की सज्ञा दी गयी। इसमें केवल 13 वाराए थी। परिसध का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका रखा गया (प्रथम धारा)। परिसंध का सदस्य वनने के पश्चात भी प्रत्येक राज्य अपनी सत्ता एव

अमेरिकी स्वतातता का यह युद्ध 19 अक्टबर, 1781 ई तक चलता रहा और इस चय ग्रेट ब्रिटेन में संयुक्त राज्य अमेरिका नी स्वतातता को स्वीकार किया । 1783 इ में परिस्त सीच द्वारा इसको मा यता दी गयी ।

स्वत प्रता का स्वामी बना रहा। इसे उसने सघ की स्थापना के समय समर्पित नही किया। तत्कालीन तेरह उपनिवेशा ने अपनी सुरक्षा एव स्वत त्रता के रक्षाय तथा सामाय हिता की पूर्ति के लिए परिसघ में प्रवेश किया था। उन्होंने आतमण की अवस्था मे एक दूसरे की सहायता का वचन दिया। सयुक्त राज्य सध की एक काँग्रेस (विधानमण्डल) की स्थापना की गयी जिसे वदेशिक मामला का निणय करने, सिक्के . एव नाप-तोल म समानता स्थापित करन, जल व थल सेना पर नियातण रखने, राज्या के आपसी विवादा का निणय करने के अधिकार प्राप्त थे। काँग्रेस म प्रत्येक राज्य की 2 से 7 तक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया था। काग्रेस द्वारा नियक्त एक समिति द्वारा उसके सनावसान-काल म काय किया जाता था । इस समिति में प्रत्येक राज्य का एक एक प्रतिनिधि होता था। परिसय की कांग्रेस की सामान्य हिता से सम्बर्धित मामला म स्पष्ट रूप से शक्तिया प्रदान की गयी थी, यथा-युद्ध की घोषणा एव शांति स्थापित करने, सीधयां करने, राजनयका को भेजने एव दूसरे देशा के राजनयका का स्वागत करने, यहा, ऋण लेने, नी-सेना का निर्माण, डाक व्यवस्था की स्थापना, समुक्त राज्य की सेना के उच्च अधिकारिया को नियुक्त करने की शक्तिया। 13 में से 9 राज्यों की स्वीकृति महत्वपुण निजया के लिए आवश्यक होती थी। काग्रेस की जनता पर प्रत्यक्ष रूप से नियायण करने के अधिकार नहीं ये और न उसे कर लगाने एव ब्यापार को नियानित करने की शक्ति प्राप्त थी। काग्रेस राज्या से आर्थिक सहायता की माग कर सकती थी। अत के दीय सरकार राज्यो द्वारा दिये गय धन पर निमर करती थी। परिसघ म कायपालिका और राष्ट्रीय चायपालिका की भी स्थापना नहीं की गयी थी। बीयड के अनुसार परिसद्य को पूण राज्य घोषित किया गया था परातु सघ सरकार को वास्तविक सिक्तिया प्राप्त नहीं थी। काग्रेस की समितिया के द्वारा शासन ठीक प्रकार से न चल सका । ऑलियर (Oliver) के शब्दो म परिसध की कांग्रेस राज्या के राजदतों की ऐसी सस्या थी जिसके विभिन्न विधान-मण्डला के साथ उसके सम्बाध राजदूतों के समान थे। सेना स्थापित करन के लिए उसे आना लेती पडती थी। फलस्वरूप उसे अपमानजनक एव अविवेकपूण रातें माननी पड़ती थी। जब कोई राज्य संघीय शासन को एक रेजीमें ट भेजता था तब वह राज्य अधिकारियों को नियक्त करने के अधिकार अपने पास ही रहने देता था। ऐसी अवस्था म सेना का समठन असम्भव था।" प्रत्येक राज्य जपनी सत्ता को बनाये रखने के लिए कृत-सकल्प था।

परिसप की घाराजा को 1781 ई में सभी राज्यों ने स्वीकृत किया था। स्ट्राम के अनुसार 1781 ई के परिसध द्वारा सक्षे सथ (True Federation) का निर्माण नहीं हुआ था व्यपितु एक परिसध—एक ढीलेडाले सप (a loose league)— का निर्माण हुआ था। बुदरी विस्सम के अनुसार "विरक्ष को धाराएँ बालू की रस्ती कर सहस्र थी जो निसी को भी वाध नहीं सकी।' हरसम फाइनर के अनुसार

² The Article of Confederation in 1781 constituted not a true

मयानक सकट के कारण उपनिवेश एकता के सूत्र में आवद हुए थे। परिसय को मित्रता के हेड सच की सजा दी गयी थी पर तु वह स्वतात्र राज्यों का अस तुष्ट सघ वन गया था। सप्रमुता राज्यों में निहित थी, कांग्रेस को अल्प एवं सीमित शिवितया प्राप्त थी। युद्ध की समाप्ति के फलस्वरूप कांग्रेस का नहा-सहा अस्तित्व भी ममाप्त हो गया था। "

परिसप का यह प्रमोग सघवाद के इतिहास म अद्वितीय महस्व का है।
1783 ई म ब्रिटेन से मिन के समय अमेरिकी पिन्सघ अपनी दुददा की चरम सीमा
पन पहुँच गया था। भुनरो ने परिसघ की दुबलता पर मत ब्यक्त करते हुए कहा है
कि परिसघ में कर लगाने, उटा लेने, व्यापार को नियित्तत करने एव सामूहिक सुरक्षा
हेतु सेना राने की चार शक्तिया का अमाव था। यह शक्तिया प्रत्येक शक्तियाली
शासन के लिए आवस्थक हैं।

कारित के समय मे परिसय ने यह दोष स्पन्द नहीं ये परन्त कारित के तरन्त बाद अनेक समस्याएँ उठ खडी हुई । मुद्रा-स्फीति एव मुख्य-बृद्धि ने जनता की कमर तोड दी। के द्वीय राजकोप खाली हो गया था। निश्चित समय पर राज्य अपनी दनदारी न कर सके। अ तर्राष्ट्रीय व्यापार ठप हा गया था। ऐसे समय मे कांग्रेस निष्क्रिय थी। इस स्थिति का उसके पास काई इलाज नहीं था। केंद्र एव राज्या व वरस्वर राज्यों के मध्य सम्बाध साचनीय थे। बैदेशिक सम्बाध के दीय शासन के क्षेत्रातगत वे परत कुछ राज्या ने निदेशी सरकारा से प्रयक रूप से वार्ता प्रारम्भ कर दी थी। तौ राज्या ने अपनी स्वतः त्र मेनाएँ एवं नौ सेनाएँ सगठित कर ली थी। परिसध म विभिन प्रकार की मुद्राए प्रचलित थी। प्रत्येक राज्य द्वारा अपने प्रदेश म व्यापार का नियमन किया जाता था। पडोसी राज्या के प्रति राज्यो दारा भेदभाव की शित का अनुगमन किया जाता था. फलस्वरूप राज्या म प्रतिस्पर्दा एव ईप्या अपनी चरम सीमा पर थी। 1786 ई म राज्या म गृह-पुद्ध छिड जाने की स्यिति उत्पन्न हो गयी। परिसय के सधार के सभी प्रयत्न असफान हो चने था। वार्षिणटन, हैमिल्टन एव अन्य प्रमुख नेता परिसध को सुधारने अथवा उसके स्थान पर नवीन राज्य-व्यवस्था की जावश्यकता को अनुसब करन लगे थे। परिसच के द्वारा कमजोर ने द्वीय शासन की स्थापना की गयी थीं। शक्तिशाली नन्द्रीय शासन क लिए

federation, but a confederation, a loose league, a 'rope of sand' as Woodrow Wilson called these Articles, 'which could bind no one "-Strong, C F op cit, p 108

³ Finer, H op at , p 169

^{4 &}quot;Especially it was weak because it lacked four things which every strong National Government must possess, ability to raise revenues by taxation, to borrow money, to regulate commerce and to provide adequately for common defence by raising and supporting armies"—Munro W B, cated by Mahajan V D Select Modern Governments 1964, p 132.

राष्ट्र की जनता की सरकार होना आवस्यव था। फलस्वरूप सितम्बर 1786 ई में अनापालिस (Annapolis) नामव स्थान पर सेरीलैण्ड (Maryland) एव वर्जीनिया (Virginia) राज्यों के यध्य पोटोमैक (Potomac) नदी म नौवालन के प्रश्न पर उत्पन्न विचाद पर विचार हेतु राज्यों के प्रतिनिधियों ना एव सम्मलन आयोजित हुआ। ए एकजेण्डर हीमस्टन इसम एक प्रतिनिधियों ना एव सम्मलन आयोजित हुआ। ए एकजेण्डर हीमस्टन इसम एक प्रतिनिधियों ना एव सम्मलन निश्चित हैं, अत सम्मलन म सभी राज्यों से अपने-अपने प्रतिनिधियों को मेजने के लिए एक प्राची जिससे परिसय के सविधान में परिस्थितयां के अनुसार आवस्यक परिवतन किये जा सके। अत सभी राज्यों के प्रतिनिधियां को एक सम्मलन मई 1787 ई म एक्लाडेलफिया म कामित किया गया। एक्लाडेलफिया म कामितन किया गया।

फिलाडेलफिया के सम्मलन म विभिन्न राज्या के 55 प्रतिनिधिया न भाग लिया था। इन प्रतिनिधिया म वाशियटन, जेम्स मेडीसन, एलेक्जेण्डर हैमिरटन, बेन्जामिन फकलिन, एडमण्ड रेनडोल्फ सहस प्रसिद्ध एव अनुमवी राजनीतिन एव विद्वान भी थे। प्रत्येक राज्य को एक मत प्राप्त या । सभी कार्यवाही गुप्त यी और बाद कमरे में हुई थी। सम्मेलन के समल बहुत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न राज्यों की स्वतान सत्ता एवं के द्रीय शासन की शक्तिया म एक्ता स्थापित करना था। मेडीसन ने अनुसार इस समस्या के समाधान हेत् प्रतिनिधिया न सिद्धातत यह स्वीकार किया कि के दीय सरकार के नवीन एवं सामाय होने के कारण उसकी शक्तिया का स्पष्ट रूप म उन्लेख उचित हागा और शेप शक्तिया राज्यों को प्राप्त होनी चाहिए। केंद्रीय सरकार की मुद्रा, व्यापार, युद्ध, युद्ध की घोषणा एवं शांति-स्थापना के अधिकार देकर यथाय म शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया गया था। सर्विभान को प्रमावी एवं जिया वित होने के लिए 13 म से 9 राज्यों की स्वीकृति आवश्यक मानी गदी । 1787 ई के अन्त तक देवल 3 राज्या न सविधान को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। इस समय एक विवाद उठ खडा हुआ था। केंद्र की प्रदत्त शक्तियों के कारण अनेक राज्य चिकत थे। सम्मेलन में सधवादी-फेडरलिस्ट (Federalists)-एव मध विरोधी-फेडरलिस्ट विरोधी (Anti Federalists)-दो गृद वन गर्म थे। सघवादी शक्तिशाली के दीय शासन के समयक थे। सघ विरोधी स्वायत्तना प्राप्त राज्या के दीने दाने सप के निर्माण के समयक थे। वे राज्या की स्वत बता एव म्बायलता न पक्षपाती थे । अनेक नेताओ-यथा, पंटिक हेनरी (Patric Henry) एव रिचाड हेनरी ली (Richard Henry Lee)-न मविधान की इस आधार पर आलोचना की कि मौलिक अधिकारी का उसम उल्लेख नही है । फेडरलिस्टा ने इस माग का समधन किया कि नवीन सरकार बीधानिशीध मौलिक अधिकारा का सविधान म समावेश करे । परिकामस्वरूप नवीन सरकार वे प्रथम दम संशोधनी नी स्वीकार करक मौतिक अधिकारों को सविधान म स्थान प्रदान निया । इसने परचात

अनंक राज्यों ने सविधान को स्वीकृति प्रदान की और 21 जून, 1788 ई से सविधान लागू हुआ 15

सघीय व्यवस्था का स्वरूप

अमेरिकी सविधान द्वारा सघीय शासन की स्थापना की गयी है। प्रारम्म मे 13 घटक राज्य ये लेकिन अब सयुक्त राज्य अमेरिका के सघ मे 50 राज्य है। सघ शासन की स्वीकृत एव माय तीन प्रमुख विशेषताओं का अमेरिकी संघीय व्यवस्था के निमाण एव विकास के आधार पर ही निर्धारण हुआ है। वे है कमश (1) लिखित एवं कठोर सविधान, (2) शक्तियों का विभाजन, एवं (3) निष्पक्ष न्यायपालिका । सविधान द्वारा संग्रीय शासन की शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अविशिष्ट जिल्ला राज्या को प्रदान की गयी हैं। केन्द्रीय शासन एवं राज्यों के मध्य शासन की शक्तिया के वितरण के सम्बाध में संबक्त राज्य में भणना एवं अवशेप के सिद्धान्त (Principle of Enumeration and Residuam) का पालन किया गया है। इस सिद्धात के अत्तगत केन्द्र या राज्यों में स किसी एक की शक्तिया का उल्लेख कर दिया जाता है और शेष शक्तिया दूसरे शासन की समभी जाती है। अत अमेरिकी सविधान द्वारा कमजोर के दीय शासन का निर्माण किया गया था। अपेक्षाकृत राज्य अधिक शक्तिशाली थे। सविधान के 10वे सशाधन द्वारा रहे-सहे स देह का भी निवा-रण कर दिया गया । इस संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गयी कि "सविधान द्वारा जो शक्तिया केद्र को नहीं दी गयी है और न राज्या के लिए वर्जित है ने सब शक्तिया राज्यो व जनता के लिए सुरक्षित है।" अत सविधान के अनुसार कडीय शासन को प्रदत्त शक्तियों के अलावा कोई अ य शक्तिया प्राप्त नहीं थी।

राज्यों के हिता को एक ज्य व्यवस्था द्वारा भी सरक्षण प्रदान करने का प्रयत्न किया गया है। सिवधान द्वारा जमरिकी काग्रेस के उच्च सदन—सीनेट—मे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व अर्थात् प्रति राज्य को दो सदस्य 'प्रेजने का अधिकार प्रदान किया गया है। सीनट को राष्ट्रपति के द्वारा की गयी तियुक्तियों एव सिधया को अनुमोदित करन एव वितीय मामला भ पूण द्वाक्ति प्रदान की गयी है। प्रत्येक राज्य को सीनट म प्राप्त समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में सवैधानिक सशोधन द्वारा परिवतन का निर्मेष है। स्पष्ट है कि इन व्यवस्थाना द्वारा राज्यों के प्रतिचिध सदन —सीनेट—को के द्वीय शासन म निर्णायक अधिकार प्रदान किये यह है।

⁵ सिविधान के अनुन्देह 1 के अन्तमत कांग्रेस को निम्निलिखित विषयो पर विधिनिमण का अधिकार दिवा गया है कर लगाना एव उन्हें एकदित करना, ऋष देना एव सबुक्त राज्य अमेरिका की मुरक्षा एव सामाय कल्याण की व्यवस्था करना, ऋण तेना, विदेखों व्यापार, नायरिकीकरण (Naturalisation) एव दिवालिया सम्य पी तिसमो का निर्माण, ब्राह्मपार एव नाप प्रणाली, डाकघरा की स्थापना, विनान की प्रगति, यवाँच्य नायालय के अधीन सधीय यायालया की स्थापना, युद्ध की घोषणा, सेना एव नौसेना।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य की केन्द्र से पृथक अपनी सर्वधानिक व्यवस्था. यायपालिका एव नागरिकता है। अमेरिका म दोहरी, संघीय एव राज्यों की याय पालिका है। सघीय न्यायपालिका के शीव पर सर्वोच्च यायालय है। उसे सघीय सविधान की व्याख्या, सम एव राज्य तथा राज्या के मध्य, एक राज्य के नागरिक एवं अप राज्य या नागरिक के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादा में मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है । सर्वोच्च "पायालय सविधान की व्याख्या का अन्तिम "यायालय है ।

सविधान म सद्योधन की स्पष्ट व्यवस्था है प्रत्यक सवधानिक संशोधन के प्रमावी होन के लिए उसे तीन-चौथाई राज्यों के विधानमण्डलो या इस हेतु बुलाय गय राप्द्रीय सम्मेलना (Conventions) के द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। अत सर्वि-धान में संशोधन के लिए राज्यों ने वहमत की स्वीकृति आवश्यक है। 2/3 राज्या के विधानमण्डला का सविधान स सशाधन प्रस्तावित करने का भी अधिकार है।

सधीय ध्ययस्या का के टीकरण

सघीय शामन का अमेरिकी सविधान के उपबाध के अन्तरात शक्तिशाली नही बनाया गया था । उसकी शक्तियों का सविधान म स्पप्ट उल्लेख करके उसे सीमित अधिकार प्रदान किया गये थे परात आज स्थिति मित है। सधीय शासन राज्यों की अपेक्षा कही अधिक शक्तिशाली है । सभीय शासन की शक्तियो म बृद्धि अर्थात सधीय के द्रीकरण के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण संघीय यायपालिका है। इसके अतिरिक्त विधायी एवं प्रशासकीय व्याख्याओं के फलस्वरूप भी कांग्रेस की डाक्तिया में प्रयाप्त बृद्धि हुई है । के द्रीय विलीय अनदान, मरक्षा एवं युद्ध, अ त राज्यीय व्यापार संघीय के द्रीकरण के लिए उत्तरदायी अय कारण हैं।

अमेरिकी सर्वोच्च 'वावालय तथा सचवाट

संघीय शासन की शक्तिया की वृद्धि में मर्वोच्च याया गय का प्रमुख भौगदान है। सधीय शासन का इड करने म निषायक भूमिका 1801 ई से 1835 ई तक अमेरिकी सर्वोच्च यायालय के मुख्य यायाधीय, जॉन माश्चल ने निमाई है। यह 'यायाधीश सघवादी (Federalist) या । उसने द्वारा प्रसिद्ध विवाद-मारवरी बनाम मेडीमन-मे दिये गये निषय के फलस्वरूप सधीय यायालया को सविधान की व्याप्पा करने एव काग्रेम की विधिया को अवैधानिक घोषित करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 1819 ई के मेकलोच बनाम मेरीलैण्ड विवाद म दिय गय निणय के द्वारा काग्रेस की निहित शक्तिया के सिद्धात (Theory of Implied Powers) का विकास हजा और सघीय सर्वोच्चता की घारणा की स्थापना हुई थी। दोना सिद्धा तो ने इससे भी आगे बढ़कर शक्तिया के परिणामात्मक सिद्धा त' (Theory of Result-

⁶ An implied power is 'a power that is deducible from an express

A resultant power is a power that is deducible from two or more express powers "

ant Powers) की घोषणा की । परिणामात्मक दक्ति दो या अधिक व्यक्त दक्तियो से परिणाम रूप म अनमानित शक्ति होती है । निहित शक्तियों के सिद्धा त के परिणाम-स्वरूप सुघीय क्षेत्राधिकार म असावारण वृद्धि हुई । ग्रक्तियो के परिणामात्मक सिद्धा त पर यायपालिका के अतिरिक्त अय कोई सीमा या प्रतिबाध नही होता है। है निहित शक्तियां सविधान की सक्षिप्तता का परिणाम है। सविधान के जत्यात सक्षिप्त होने के कारण संघीय ज्ञासन को प्राप्त शक्तिया अत्यात अस्पन्द हैं और उनके प्रयोग करने की विधि का भी कोई उल्लेख संविधान म नहीं है। अत यह स्वामाविक है कि मूल शक्तिया के प्रयोग के लिए जिन अय शक्तिया के प्रयोग की आवश्यकता प्रतीत हो. उनका प्रयोग संयोग शामन मुल शक्ति में निहित मान कर करे। सविधान के जनुष्छेद 1 व B म सविधान द्वारा प्रदत्त शक्तिया के निया वयन के लिए उनस सम्बर्धित इक्तिया को काग्रेस भ निहित माना गया है। इसका यह अथ है कि काग्रेस को सविधात दारा प्रदत्त एव उनम निहित विक्तियों के प्रयाग का संवधानिक आधार तो प्राप्त था परन्त निहित शक्तिया को विधिक मा यता यायाधीश माशल के उपरोक्त विवाद म निणय द्वारा ही प्राप्त हुई। निहित शक्तिया की धारणा का समयन सब-प्रथम 1790 ई म तत्कालीन वित्त मात्री हेमिल्टन ने बैदेशिक एव अन्त राज्यीय व्यापार के लिए सयुक्त बैक की स्थापना के सादम म किया था। इस प्रश्न को लेकर कांग्रेस मे विवाद उठ खडा हुआ। उदार सविधानवादियों का मत था कि सविधान की व्याख्या उदार हिंग्टिकाण से की जानी चाहिए और मुल शक्तियों के उपभोग के लिए जित आय शक्तिया की जावश्यकता हो वे संघीय बासन की मूल शक्तियों म ही निहित समभी जानी चाहिए । इसके विपरीत जैफरसन, मेडीसन सहश सविधानवादी भी ये जो सर्विधान के अक्षरश पालन के पक्षपाती थे। परन्तु इस विवाद का निगय हेमिल्टन के पक्ष मे हुआ और एक सघीय बक की स्थापना हुई। इस निणय म अथात् बक की स्थापना में निहित शक्तियों की बारणा स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। बक की स्थापना कोई नीति सम्बाधी निणय नहीं था अपितु वह विशेष मामले सं सम्बाधित था। निहित शक्तिया को सिद्धा त रूप मे 1819 ई के मैकलोच बनाम मेरीलैण्ड के मुकहमे म यायाधीश माशल के निणय द्वारा स्वीकार किया गया तथा सधीय सर्वोच्चता और निहित शक्तियों को पण मायता प्राप्त हुई। इस निणय में कहा गया था कि "शासन की शन्तिया सीमित है और उनका अतित्रमण नही किया जा सकता. पर तु हमारा यह विचार है कि सविधान के स्वस्थ स्वरूप के अनुसार राष्ट्रीय व्यवस्थापिका को स्वविवेव से काम लेने की अनुमति अवस्य ही होनी चाहिए जिससे सविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियो को उसके द्वारा नियाचित किया जा सके तथा वह सस्था अपने निर्धारित महान कतव्यो को ऐसे ढग से पूरा कर सके कि वे जन-साधारण के लिए सर्वाधिक लामकारी हा । " सर्वोच्च यायालय ने सघीय शासन द्वारा स्थापित

Refer to Dimock & Dimock American Government in Action, p 134

'The powers of the government are limited and its powers were

वक पर राज्यो द्वारा कर लवान के अधिकार को स्वीकार नहीं किया। सर्वोच्च गायालय का इस सम्बाध म मन वा कि सबीय सस्याआ पर राज्या का कर लगाने के अधिकार वा स्वीकार करने का अब उस समाध्य करना है। अत सर्वोच्च गायान्य ने यह अनुमति प्रदान करने से इचार कर दिया। निहित शक्तियाँ सासन की ये शिवना है। के अप आसन की मूल पित्तमा को वियाचिन करने के उद्देश्य स उसम निहित मानी गयी है। निहित शक्तियाँ कोई नवीन शक्तियाँ नहीं हैं अपितु व मूल सिन्यां का अब है। वे मूल शक्तियाँ कोई नवीन शक्तियाँ नहीं हैं अपितु व मूल सिन्यां का अब है। वे मूल शक्तियाँ को कियाचित करने के साधन मान हैं। संधीय सामन को सवियान द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ यदि साध्य हैं तो निहित शक्तियाँ सामन है। निहित शक्तियाँ निरुष्ट होती हैं। माधल के अनुसार निहित सक्तिय होती हैं। माधल के अनुसार निहित सक्ति के उद्देश 'वय एव सविधान के सेन के अपत्त होती हैं। माधल के अनुसार निहित सक्ति के उद्देश 'वय एव सविधान के सेन के अपता होत चाहिए और उनके साधन मी बधानिक होन चाहिए।'

निहित गोक्तिय। के मिद्धान के प्रमावस्वरूप संधीय शासन का अपने दायित्वा के सम्पादन म सहायता प्राप्त हुई और सविधान का विकास हुआ तथा परिवर्तित परिस्थितिया के अनुमार उनसे आवश्यक परिवर्तन हात रहें। इसने अतिरिक्त, सासन सिंग को के हीकरण हुआ और शासनतन्त्र म स्थायपालिका के महत्व म बिंद हुई। निहित दाक्तियों के नारे म कांग्रेस अनित्म निर्णायक नहीं है अपितु सवींक्य पानावस अनित्म निर्णायक महत्व म अपने स्थापन अपने स्थापन अपने स्थापन अपने स्थापन अपने स्थापन स्थापन अपने स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप

हरिटनीण का अस्वीकार कर दिया है।

यायाधीश माशल ने मैकलोच बनाम मरीलंण्ड के विवाद म निणय देते हुए कहा या कि 'समुक्त राज्य अमेरिका जनता का सप है और केन्द्रीय सरकार सिद्धाल एव व्यवहार दोना म ही प्रत्यक्ष रूप से जनना पर निमर रहने वाली राष्ट्रीय सरकार है।' इस निणय के माध्यम से माशल हारा इस वात पर वल दिया गया है कि केन्द्रीय शासन को शांका राज्यों स प्राप्त न होकर प्रत्यक्षत जनता से प्राप्त है। सिंव धात तो कवल एक स्वरूप है जिसके ज तगत राष्ट्रीय सरकार विकास कर मकती है । सां ज से विकास करना चाहिए। इसी विवार को पुष्टि यायाधीश होस्स (Justice Holmes) ने एक अन्य विवाद सिसीरी बनाम हालक्ष्ट) म की है।

केंद्र द्वारा राज्यों को प्रवत्त विसीय सहायता

10 Article 1, Sec F, Clause 1

यह केद्र की दक्ति की बृद्धि का एक अध कारण है। केद्र द्वारा राज्या की आधिक अनुदान कराधान धारा¹⁰ (Taxation Clause) के अन्तमत दिया जाना है।

not to be transcended But we think the sound construction must allow the National Legislature that discretion with respect to the means by which the powers in confers are to be carried into execution which will enable that body to perform high duties assigned to it in a manner most beneficial to the people '— Marshall, C J, in McCullock vs. Maryland (1819)

के द्रीय शासन को इस धारा के अधीन जनकल्याण व हुतू सहायता देने का अधिकार है। राज्या की तुलना म ने द्रीय शासन की आय के स्नात अपक्षाकृत अच्छे हैं। अधिकाश समाज-क्ल्याणकारी याजनाओं का मार राज्या पर है लेकिन उनकी वित्तीय स्थिति इन अतिरिक्त दायित्वा का वहन करने म असफल है। फलत राज्यों को केद्रीय वित्तीय जनुदान पर निभर रहना पडता है। कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य जादि से सम्बन्धित जिन जन-यत्याणकारी याजनाजा के लिए सघीय जासन द्वारा राज्यो को अनुदान दिया जाता है, सधीय शासन का इस अर्थिक अनुदान को व्यय करने से सम्बर्धित नियमा को निविचत करने का अधिकार हाता है। प्रारम्भ में सभी अनुदान विना शत दिये गये ये परन्तु जब सभी अनुदान सशत (conditional) हाते है। के द्र को के द्रीय अनुदान से सम्बर्धित राज्या ने कार्यों के निरीक्षण एव हिसाय की जाच करने का अधिकार है। परिणामस्वरूप राज्या की स्वायत्तता सीमित होती जा रही है और राज्या के कार्यों पर के द्रीय दासन का नियानण बढता जाता है। के द्रीय शासन द्वारा सडका, वन, सामाजिक सुरक्षा, कृषि के विकास व सावजनिक कार्यों के निर्माण तथा वेरोजगारी, सुरक्षा एव शिला जादि पर कुल व्यय का औसतन 50% अनुदान दिया जाता है। 1933 ई के बाद के द्वीय शासन ने नगरपालिकाओं को भी सीवे आर्थिक अनुदान देना प्रारम्भ कर दिया है।

सामाजिक परिवतन

सामाजिक परिवतन, युद्ध एव अ तराष्ट्रीय स्थिति के फलस्वरूप भी अमेरिकी के द्रीय शासन की शक्ति से वृद्धि हुइ है। 1789 ई स सयुक्त राज्य अमेरिका कृषि-प्रधान जय-ध्यवस्था वाले 13 उपनिवद्यों का कम जनसरया बाला देश था । आज वह 50 राज्या का प्रधान औद्यागिक देश है और जावादी की हृष्टि से भी एक वडा देश है। 1917 ई तक अमेरिका ने वैदेशिक मामला में पृथक्करण की नीति का अनुगमन किया था। आज वह विश्व की महान शक्ति है, अंतरिष्टीय राजनीति म परिचमी उदारवादी लोकता निक शक्तियो का प्रमुख पक्षांबर है तथा लोकता निक शक्तियो एव विश्व शाित की रशा के दायित्व को ओढें हुए है। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय सरकार के वायित्वों में सहजही वृद्धि हुई है और उसी अनुपात में उसकी शक्ति में भी विद्ध हुई है। सधीय शासन के प्रति जनता के हिष्टिकाण पर इन परिवतना का प्रभाव पड़ा है और जनता राष्ट्रीय शासन की शक्तियों म विद्ध के प्रति सहज ही सहिष्णु हो गयी है। यातायात एव आवागमन तथा नवीन वैज्ञानिक सचार व्यवस्था के द्वागासी साधना के विकास के परिणामस्वरूप देश के विभिन्न क्षेत्रा की पृथकता नष्ट हो गयी है। औद्योगिक एव व्यापारिक हिन्द से संयुक्त राज्य अमेरिका एक सुदृढ इकाई वन चुका है। इसक स्वामाविक परिणामस्वरूप राज्यो की शक्ति म हास हुना है और क द्रीय शासन अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली होता चला गया है। व्यापार एव औद्यो-गिक विकास से उत्पान समस्याओं के समाधान की क्षमता राज्या म नहीं थी।

राष्ट्रीय स्तर पर दला के सगठन एव विकास न राज्या की सीमाआ को समाप्त

नर दिया है। दला द्वारा शंत्रीय एवं राज्या की हृष्टि की अवशा राष्ट्रीय हृष्टि से नीति निधारित की जाती है। राष्ट्रीय ममानार-गत्रा के विकास । सामाच राष्ट्रीय आद्यों में स्वापना में बाम दिया है और जन्मा में राष्ट्रीय एकता का धाना उसल मी है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय एकता का द्वार बन बया है। लास्त्री वा क्यन है हि राष्ट्रपति की प्राप्तिया का विकास अमरिकी संधीय स्ववस्था में महत्वपूण परिवतन है। सुरक्षा एवं पुढ

मबधानिक हिन्द्र ॥ मन्ति राज्य अपरिका की मुक्ता, विद्या आफ्रमण स रक्षा और युद्ध का दावित्व मधीव पामन का है। आज मुरगा का स्वरूप पूरी तरह बन्ल बुरा है । पुत्र ने प्रारम्भ होते तक मुरुशा । निम देश नही रहा जा सरता । मुरक्षा र निम्मतत तयारी अपनित है। राष्ट्र की मुरक्षा हुनु सम्पूण औदापित एव तरनीती तथा आधित एव मानवीय शक्ति का इत प्रकार समायाजन जायस्यक है कि विसी भी जाम्मावित परिस्थित का महत्व ही मामना रिया जा गर । इसर निए जल्पादन यानायात, मचार जिनिमय-व्यवस्था एव मानवीय साधना पर निवन्त्रण आव-रपन है। यह दायित्व संघीय द्यासन हो नली मौति निमा भी सरता है। युद्ध प्रारम्भ हान पर इस दायित्व म और अधिर बद्धि हो जाती है। पुद्ध क बाद सना व विस मी-बरण एव युद्धोत्तर पून निमाण व लिए उचित नियानन एव समानम की अपशा होती है। राष्ट्रीय अवात संघीय शासन को पुद्ध वी पापणा करन का अधिकार है। सफलतापूर्वर युद्ध-संचालन क लिए पूर्ण शक्ति की आवश्यकता हाती है। विशत दी विदय युद्धा क फलस्वरूप संघीय नासन की शक्तिया म असाधारण विकास हुआ है। लियोनाड न इस सत्य का व्यक्त करत हुए यहा है कि 'रुसी मालू यह स्पष्ट राक्षस है जो हम बाद की तरफ धक्त रहा है। अत बाह्य आत्रमण एव अनुरक्षा का नय संयुक्त राज्य अमरिका के वे दीय शासन को अधिनाधिक शक्तिशाली बना रहा है। अन्त राज्यीय व्यापार एव वाणिज्य

अत राज्यीय ब्याजार एवं वाषिज्य ने सपीय ने श्रीकरण को बहुत बस दिवा है। सिवधान ने विदेशी राज्या एवं विधिन राज्या के मध्य याणिज्य न नियमत ने सिक्त नोध्रेस नो प्रदान को है। भे यही वाणिज्य धारा (Commerce Clause) नह- काती है। इसने सम्बन्ध म हीमत्टन ना मत था कि व्याधारिक एवं राजनीतिन हितों की पूर्ति शासन की एनता म ही सम्मत है। मैं आज अमेरिका का जन्त राज्यी प्रविचित्त वाषापर बहुत वह गया है। इससे सम्बन्धित उत्पादन, प्रम विभ्न्य, साताप्रविक वादि सम्बन्धी को ज्यापर यहुत वह गया है। इससे सम्बन्धित उत्पादन, प्रम विभ्न्य, साताप्रविक वादि सम्बन्धी अनुसत मं नविस की बक्तिस म भी वृद्धि एवं विकास स्वाधानिक वृद्धित के साथ उसी अनुसत म नविस की बक्तिस म भी वृद्धि एवं विकास स्वाधानिक

12 The Federalist, No 11

¹¹ The 'power to regulate commerce with foreign nations and among several States III granted to the Congress by the U E Constitution vide Article 1, Sec VIII Clause 3

है। सर्वोच्च पायालय ने इसी दृष्टिकोण का समर्थन किया है। फलस्वरूप व्यापार एव वाणिज्य से सम्बिध्त समस्त सथीय विविधा एव उनके किया वयन को यायालय ने मायता प्रदान की है। इससे देश के आधिक जीवन का हर क्षेत्र के बीय शासन के क्षेत्रादिकार के अत्तवत आ गया है। 1824 ई मे पायाधीय माशल ने वाणिज्य धारा (Commerce Clause) की व्यापक परिमापा दी जिससे सभी औद्योगिक एव याणिज्य विकास के काय, जैसे—देलमान, टेलीफोन, रेडियो, हवाई यातायात, स्वत ही सधीय नियत्रण मे आत बले गये। 13 पर सु 1868 ई म सर्वोच्च पायालय ने यह निषय दिया कि बीमा पर सथीय नियत्रण को अत्वता राज्यों का नियत्रण हाना चाहिए। केकिन 1944 ई मे सर्वोच्च पायालय ने अपने इस पूर्वानणय को बदलते हुए बीमा पर भी सबीय नियत्रण एव अधिकार स्थापित कर दिया है।

1937 ई में सर्वोच्च यायालय ने एक अप्य विवास में में निणय देते हुए अमिक सन्व को (Labour relations) को भी संधीय झासन की वाणिण्यिक शक्ति के अधीन माना था। फलस्वरूप राज्यों का को इन मामला में निय ने प्या, वह समान्त हो गया। 1939 ई में कृषि-उत्पादन को भी सर्वोच्च यायालय ने संधीय नियन्त के अधीन स्वीकार किया था।

वाणिज्य नियमन की श्रीक्त का क्षेत्र अत्य त व्यापक है। व्यापार का प्रशासम एव उससे सम्बिध्त समस्त नियमा का निर्माण वाणिज्य नियमन के ही अ तगत है। इसके असिरिस्त, एक या अधिक राज्यां स सम्बिध्त व्यापार या वाणिज्य की पुरता, विकास एव परिवद्धन वाणिज्य के नियमन के ही अत्यत्व आता है। अत अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था का कोई क्षेत्र ऐका नहीं है जो के दीय शासन के स्नेताधिकार के अ तगत न हो। 1930 ई स 1940 ई तक के वर्षा में कांग्रेस ने वाणिज्य धारा का उपयोग अभिक-सम्बचो, रेडियो के निय नण, रेलवे कमचारियों के लिए अवकाश व्यवस्था प्रदान करने, अन्तर्राज्यीय वस एव ट्रक यातायात के नियमन एव यातायात सम्ब धी नियमों के निमाण के लिए किया है। कांग्रेस द्वारा निर्मित इन समस्त विधिया के कांग्रेस राज्यों की शक्तियों का हास हुआ है और संधीय सरकार द्वारा उनके क्षेत्र का अतिकरण हुआ है।

काग्रेस द्वारा अनेक प्रशासकीय विभागो एव आयोगा की स्थापना की गयी है और उनने सन्वर्ध पत विधियो का निर्माण किया है। इसके फलस्वरूप राज्या की शक्ति के मूल्य पर सधीय झासन की शक्ति म विद्य हुँ है। सधीय व्यापार आयोग, सधीय रिसम वीव पुत्रगठन विसीय निगम, राष्ट्रीय भागे को सामाजिकमुरसा बोड आदि ऐसे कुछ आयोग है। काग्रेस द्वारा अनेक ऐसी विधिया वा भी निर्माण किया गया है जिनके फलस्वरूप सधीय सासन की श्वितसी म वृद्धि हुई है, जसे अन्त वाणिज्य

 ¹³ Gibbons vs Ogden, (1824) S C
 14 N L R B vs Jones and Laughten Steel Corporation, (1937) 301
 U S I

अधिनियम, खाच एव औषधि अधिनियम, सघोय व्यापार आयोग अधिनियम एव सरमत विधि । ¹⁵ इन सभी वांडों को स्थापना एव विधिया का निमाण सामाजिक परि स्थिति का परिणाम है ।

मूल सविधान म यह प्रावधान था कि प्रत्यक्ष करा से प्राप्त हान वालों जाप सभी राज्या म विवरित की जायगी। गृह मुद्ध वाल म आय-कर कायेन के द्वारा आरी किया गया था। सर्वोच्च प्रायालय ने इसे अप्रत्यक्ष कर मानत हुए बायक की इन विधि को वैध माना था। 12 लेकिन 1895 ई म सर्वोच्च प्रायालय न अपने इस निजय को बदल दिया। 12 अत आय कर अधिनियम का वधता प्रदान करन के लिए 1913 ई में सर्विधान म सराधन करना पड़ा था। 18

क्सी राज्य को सयुक्त राज्य अमरिका ने सघ स प्रथम होने का अधिकार नहीं है। इस सिद्धात का सम्बाध अमरिको इतिहास की एक महत्वपुण घटना से है। 1861 65 ई के गह-युद्ध या सब स प्रयक्त होने सम्बाबी युद्ध (Civil War or the War of Secession 1861-65) न इस सिद्धात की स्थापना की थी। राष्ट्रपति लिकन ने दासता के उपलब्ध की घोषणा की । दक्षिण के सात राज्यों न इसका विरोध निमा । विरोध उग्ररूप धारण करता अला गया और गृह युद्ध छिड गया । इस युद्ध म दक्षिण के सात राज्य पराजित हए और उनके विरुद्ध संघीय शासन की विजय हुई। लिकन के द्वारा यह गह युद्ध केवल दासता के उ मुलन के लिए ही नहीं लडा गया थी अभित इसके द्वारा सचवाद के इस जीवनदाया सिद्धा त की स्थापना हुई कि सच घारवत है। लिंकन का कथन था कि हम यह निश्चयपुरक कह सकते हैं कि किसी देग के मविधान म उस देश के झासन की समाप्त करने सम्ब मी कोई प्रावधान नहीं होता ! आज अमेरिका का कोई राज्य प्यक होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। गृह पुढ ने आत के परचात सधीय शासन विजयी एव शक्तिशाली अवतरित हुआ। स्ट्रांग का कथन है कि 'प्रयक्ता के युद्ध ने न तो अमेरिकी सविधान के स्वरूप म परिवतन ही किया और न उन्होंने एकात्मक राज्य की स्थापना की । इस युद्ध न केवल यह सिद्ध किया कि अमेरिकी संघ एकात्मक राज्य नी माति इड है और विघटन से अपनी रक्षा कर सकता है।"18

16 Springer vs United States, (S C)

¹⁵ Interstate Commerce Act Food and Drugs Legislation, The Federal Trade Commission Act and the Sherman Anti trust Act

¹⁷ Pollock vs Farmer's Loan and Trust Co., 157 U S 429 and 158 U S 601

^{18 &#}x27;The Congress shall have power to lay and collect taxes or in comes from whatever source derived without apportionment among the several States and without regard to any census and enumeration —XVIth Amendment in the U S Constitution

¹⁹ Strong, C F op cat, p 111

समीक्षा

जमरिकी शासन-व्यवस्था में संघीय के द्रीकरण के फलस्वरूप सहज रूप से यह प्रश्न उठ खड़ा हुना है कि क्या ऐसी जवस्था में संयुक्त राज्य को संघातमक राज्य माना जाना चाहिए ? इस प्रश्न का उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय शासन के स्वरूप एव उसके इतिहास पर निमर है। अमेरिकी सधीय व्यवस्था के दो काल है-1930 ई क पूर्व का काल एव उसके बाद का काल। 1930 ई की विश्वक्यापी मंदी के पूज का काल द्वध सघवाद (Dual Federalism) या प्राचीन (classical) सघवाद का युग कहा जाता है । 1930 ई की विश्वव्यापी मादी ने आध-निक या सहयोगी (cooperative) सघवाद के युग का सूत्रपात किया है। अमे रिकी सधीय व्यवस्था के लिए 'द्रंघ सघवाद' शब्द का प्रयोग सबप्रथम एडवड एस काबिन (Edward S Corwin) ने किया है। इस युग का समवाद पर उपलब्ध सम्पण अमेरिकी साहित्य इस घारणा को मा यता देता है कि दो-के द्वीय एव राज्या की-सप्रमताए हैं। वे सवर्तीय हैं और दोना अपने-अपने क्षेत्रा मे स्वतात्र हैं। 19वी मदी घर दैध सम्बाद का सिद्धा त अमेरिका सर्वोच्च यायालयों के निणयों के माध्यम से व्वतित होता रहा। सधीय या के द्रीय और राज्या की सरकारों में शक्तियों का विमाजन 'द्रैथ संघवाद के सिद्धा त' का मुलाधार है । शासकीय समस्याजी के समाधान मे शासन के विभिन्न स्तरो पर सत्ता का पृथक्करण ही द्वधवाद (Dualism) था। इस सिद्धात के अनुसार प्रत्येक शासन के अपने दायित्व थे जिन पर उसका पूर्ण अधिकार था। प्राचीन सधयाद के युग में इस सिद्धात का तीव समयन राज्यों के अधिकारों के समयका ने ही नहीं किया था, अपित राष्ट्रवादी भी इसे मा यता देते थे। ° प्रो लियोनाड डी ह्वाइट के अनुसार प्रशासन म भी द्वैधवाद पाया जाता था। दो प्रशासनिक एव "याय-व्यवस्थाएँ थी । दोनो अपने अपने क्षेत्रा मे स्वायत्त एव पुण थी।

सपुक्त राज्य अमेरिका के सर्वाच्च यायालय ने अंत राज्यीय सम्बाधा म हैध-बाद को मायता दी है। वीधकाल तक तो सर्वोच्च यायालय ने सधीय इधवाद की प्रकृति पर कोई स्पट्ट निजय नहीं दिया था। प्राधीन सधवाद से सम्बाधित मुख्य विवाद ये माटिन वनाम हटस (1816), कोहि स बनाम बर्जीनिया (1821), मैन्डोच बनाम मेरीलैंग्ड (1819) 2 एव पिक्ट स बनाम आपने । ३३ इसके अदि-रिक्त, अंत राज्यीय वाणिज्य संसम्बाधित विवादों में इधवाद क विस्तत उत्लेख प्राध्ना होता है। यायाधील माश्रल के निजया के फलस्वस्य सधीय सासन की शक्तियों म

²⁰ Elazar, D J The American Partnership 1962 ed , p 14

²¹ Leonard D White The Jacksonians 1954, p 506

²² Martin vs. Hunters Leasse (1816), Cohens vs. Virginia (1821) and McCulloch vs. Maryland (1819)

²³ Gibbons vs Ogden (1824)

असा*थारण* वृद्धि हुई है। सर्वोच्च यायालय में जैक्सनवादी रायाधीक्षों के शक्ति जान के पश्चात दासता सम्बची विवादों म दिवे गय निषय राज्यों के पक्ष में थे मुस्य पायाबीस बोजर बी टानी ने ऐबिलमेन बनाम तूप (1858) के विवाद निषय देते हुए 'ब्रैंघनाद'' की निम्नलिखित ग्रन्दों म स्वट्ट एवं अधिकृत ब्यास्य की है

"के डीय एव राज्य शासन की शक्तिया यद्यपि स्वष्ट हूं और एक ही क्षेत्रीय सीमा में किया वित की जानी है पर तु वे पृथक एवं स्पष्ट सप्रमुताएँ हैं जो अपन अपने क्षेत्रों म पृथक एव स्वतन्त्र रीति से नियाशील है।" ।

संयुक्त राज्य अमरिका के गह-युद्ध के परचात सर्वोच्च यागालय न अनेक निणया म सचीय है बाद के सिद्धात का विस्तृत जल्लेख किया है, यया-कलेक्टर वनाम डे (1871) स्लॉटर हाजस विवाद, मुनवस बनाम इलीनोइस एव पोजी बनाम फीसेनडेक्टल (1922)25। अपने एक अस निषय में मर्वोच्च यायालय के न्यासा धीश वितियम आर डे न सर्वोच्च यायालय का काय दोना सरकारों से सम्बर्धित क्षेत्रों की रक्षा करना एवं जनमें मध्यस्यता करना बताया है। है इस सम्वाद का अध सघ एव राज्या म शक्तियों के वितरण एव दोनों सरकारा के पृथक क्षेत्र एव अधिकार सं है। इस अमेरिकी संघीय राजनीतिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण तस्व माना जाता था। पर तु अ त राज्यीय सम्ब धा म राष्ट्रपति फ्रेकलिन डी रूजवेस्ट की यू डील मोजना नवयुन का सुत्रपात करती हैं। परिचितित परिस्थितियों भे एडवर्ड कार्यिन, नियोनाड डी ह्वाइट सहया विद्वामा ने हैं अवाद की पुन व्यास्था की है। उनका मत है कि सवि-धान-निर्माता एक मदाक्त राष्ट्रीय शासन का निर्माण करना चाहते थे पराबु परि-स्चितियावन उन्हे राज्यां के लिए महत्वपूण वायित्व निर्धारित करना पदा। व्यक्ष व्यवस्था का पुग लद चुका है, नवीन सपवाद (New Federalism) का उदय हुना है जिसका मारम्म जिल्लान क प्रकासन या प्रकलिन बी रूजवेल्ट के शासन से माना जाता है। नवीन सदबाद ने ढारा सदीय एव राज्या की सरकारा म जो अवरोध थे वे व्यस्त हो गर्वे हैं। फलस्वरूप सम एव राज्यों म पुषकता की अपेक्षा महयोग का विकास हुआ है । इस सहयोगी सघवाद (Cooperative Federalism) भी कहते हैं । यह परस्परा गत पुषकनावादी सपीय ड्रैथवाद स मिन्न है। सहयोगी सपवाद के परिणामस्वरूप

²⁴ The powers of the Central Government and of the State although both exist and are exercised within the same territorial limits are yet separate and distinct sovereignites acting separately and yet separate and distinct sovereignines acting separately and independently of each other within their respective spheres — Ableman vs. Booth case. U.S. Supreme Court (1858) 25 Collector vs Day (1871) The Slaughter House cases, Munx vs. Illinois

²⁶ Mr Justice William R Day in Hammer vs Dagenhari (1918)

²⁷ Ogg and Ray Essentials of American Government, p 45

सघीय ज्ञासन की जन्तिया का विस्तार राज्या के क्षेत्र म भी हो गया है। नवीन योज-नाओं के जिया बयन हेत संधीय एवं राज्या की सरकारा में सहयोग का विकास हुआ है। 18 प्राय प्रत्येक संघीय राज्य म केंद्र एव राज्या के मध्य सहयोगी तत्वो एव सस्याओं का विकास हुआ है। अमेरिका में गुवनरा का सम्मेलन इस प्रकार के सह-योग का एक उदाहरण है। प्रथम सम्मेलन 1908 ई म थियोडोर रूजवेल्ट की प्रेरणा से हुआ या । परन्त हीयर के अनुसार गवनरा का सम्मेलन राज्या एवं सघ शासन के मध्य किसी कियात्मक सहयोग का निकास नहीं कर सका है। 29 1937 ई म सयुक्त राज्य अमेरिका मे राज्या म सहयोग के विकास हेत जात राज्यीय परिपद (The Council of State Governments) की स्थापना की गयी थी। इस परिपद ने महत्वपूर्ण काय किया है।

नवीन सघवाद के प्रति मिथित प्रतिकिया हुई है। राज्या की स्वायत्तता के पक्षधर जिल्ल जफरसनवादी (Jeffersonians) कहा जाता है, इसे Coerced Federalism कहते हैं। केंद्र एव राज्यों के इस सहयोग को केंद्रीय सम्मिथण (Central assimilation) भी वहा जाता है 100 इससे राज्या की परम्परागत स्वत नता एव अधिकारों का हनन हुआ है। इसके निपरीत, हेमिल्टनवादी (केंद्र के पक्षधर) केंद्र एव राज्या के बढते हुए सहयोग का समधन करते हैं। श्री डेनियल जे इलाजार (Daniel J Elazar) न अमेरिकी सधीय व्यवस्था एव राज्यो के सम्बन्धा की समीक्षा करते हए कहा है कि "सयुक्त राज्य की संघीय वयस्था मुलत सहयोगी है और व्यवहार में द्वैध सपवाद कभी सफल रही रहा है।" 19वी एव 20वी दोना ही सदियों में सघ एव राज्यो न जासकीय दायित्वा को परस्पर सहयोगपूत्रक सम्पादित किया है। लेकिन इस सत्य का अवलोकन न कर सकन का कारण उस युग के राजनीतिक नेताओ की सिद्धात एव व्यवहार के अन्तर के प्रति वैमनस्ययुक्त नीति थी। ³¹ सघीय अनुदाना ने सहयोगी सघवाद के आधार-स्तम्म का काम किया ह।

अमेरिका के सधीय शासन की शक्तिया मे राज्य के दायित्वों मे वृद्धि के साथ-साय बद्धि स्वामाविक है। फलस्वरूप संघीय शासन की शक्तियों में असाधारण विकास हुआ है। राष्ट्रीय एकता की हृष्टि स यह आवश्यक भी है। अमेरिकी सच मे केंद्र एवं राज्यों म शक्ति सातलन उलट गया है। केंद्र की अपेक्षा राज्यों को सविधान मं शक्तिशाली बनाया गया था परातु आज स्थिति उल्टी है। लेकिन इसका यह अथ नहीं है कि राज्या का नोई महत्व नहीं है। सत्य यह है कि राज्या को आज भी पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त है। राज्यों के दायित्व भी काफी महत्वपण है। सभी अमेरिकी राज्यों म राज्य के प्रति तीव मिक्त पायी जाती है। स्मरणीय है कि 1900 ई के पुत्र असे-

²⁸ Elazar D J op cit, p 23 29 Wheare K C Federal Government p 229 30 Aiyar, S P Federalism and Social Change, (1961) p 165

³¹ Daniel J Elazar op est p 24

रिका म सघ एव राज्या के सम्बन्ध मूलत एक राजनीतिक प्रस्त था, जबकि र वह विशुद्ध आर्थिक समस्या है। हम इस मत स भी सहमत हैं कि अमेरिकी म शामन की शक्तियों म राज्या भी शक्ति क मृत्य पर विद्व हो रही ह पर त स्टा इस मत का भी हम स्वीवार करना पड़ेगा वि 'सयुक्त राज्य म सपीय सविवान राज्या के सविधाना स जा उसके स्वात उपयोगी एव अनिवास अग हैं, पुश्क र जय नहीं है।"³

आस्ट्रेलिया की सघीय व्यवस्या

आस्ट्रेलिया के नविधान म सधीय शासन की समस्त विशेपताएँ-पया, स बान की सर्वोच्चता के द्रीय एव राज्या की सरकारा के मध्य शक्तिया का विमा एव सविधान की व्यारमा करन के लिए स्वतात्र पायपालिका--पायी जाती हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एव विकास

आस्ट्रेलिया म सधीय व्यवस्था का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका और करा की अपेक्षा बहुत भिन्न रूप म हुआ है। 1863 ई म ग्रेट निटेन न आस्ट्रेनिया मः द्वीप के अपने छ उपनिवेद्यों का पुनगठन पूज कर लिया था । इस समय इन राज के समुद्रततीय प्रमुख नगरा म तोव जायिक प्रतिस्पर्धा थी। इन छ नगरा म स्यानी व्यवस्थापिकाएँ थी और उनक अधिवरान भी होत थे।

सभी राज्य क्षेत्रफल म विशास ये और एक दूसर स काफी दूर ये। उन मध्य आवागमन के सम्चित साधना का अभाव था। फलस्वरूप प्रत्यक राज्य में पृष् कता की भावना विकसित हो चकी थी। उपनिवसा के मध्य एकता म सामा पुल्क व अंची दरे वापक थी । विकटोरिया, दक्षिण आस्ट्रेलिया एव पू साउप वेल्स के राज के हित एक समान था छाट राज्य वडे राज्यों को सदेह एवं ईप्यां की हिन्द से देख थे। निथन राज्या को यह भय था कि संघीय व्यवस्था से कर मार म वृद्धि ने जाये। फलत इस समय मधीय शामन की स्थापना के सभी प्रस्ताव जसफल हो पु थे। परातु जास्ट्रेलिया म सघ शासन की स्थापना म सुरक्षा के प्रभावशाली तत्व पर्याप्त योग दिया है। न्यू केलेडोना पर फ्रांम प्रमुख स्थापित करना चाहता था जमनी यू गिनी के एक माग पर अधिकार जता रहा था। इगलण्ड व रूस म युद्ध के सम्भावना थी। जास्ट्रेलिया के पूर्वी राज्या की सुरक्षा को जमनी के यू गिनी के प्रमुर्त स सकट उत्पन्न हो गया था । इंगलण्ड ने आस्ट्रेनिया के उपनिवेशा की सुरक्षा क दाधित विना उनके सहयोग के वहन करन स इकार कर दिया था। नास्ट्रेनिया वे राज्यों म आत्रमण की आशका के कारण मुख्या के निए एक आदीवन का सूत्रपति हो गया था। यू साउथ वत्स के प्रधान मात्री के प्रयत्ना क परिणामस्वरूप 1819 ई म सभी उपनिवेशा रा एक राष्ट्रीय सम्मलन शुनाया गया। इसके बनिरिक्त मध के निर्माण म आधिक तत्व भी सिन्य था। प्रत्येक उपनिवैश न सीमा शत्क की ऊची दरे

³² Strong C F op at p 110

लगा रखो भी जिससे व्यापार वाणिज्य म वाधा उत्पन्न होती भी। कुछ उपनिवेश आधिन इंटिट से अनिकसित भी थे। उनके लिए रख मार्गा का स्वत न रूप म कायम रखना सम्मव नहीं था। फ्लस्वरूप कृषि का विकान नहीं हो पा रहा या।

1891 ई के उपयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन म विभिन्न महत्वपूर्ण निणय लिये गये, अ यथा — आन्तरिय क्षेत्र म व्यापार भी स्वत तता, वित्तीय एव मुरक्षा नीति पर के द्रीय नियम्भण एव एक सपीय सत्ता द्वारा प्रशासन । 1897 ई म दूसरा राष्ट्रीय सम्मलन आयोजित किया गया । इस सम्मलन म प्रयम सवधानिक प्राप्त्य स्वीकृत नहीं हो सका । कुछ व्यवस्थापिया द्वारा प्रस्तुत द्वितीय सवधानिक प्रार्थ्य सभी राज्या द्वारा स्वीक्ता किया गया । पिरवमी आस्ट्रेलिया न पृथक राज्य पा वजा प्राप्त करन पर हो सविधान के प्राप्त पा परिवमी आस्ट्रेलिया न पृथक राज्य पा वजा प्राप्त करन पर हो सविधान के प्राप्त पा परिवमी आस्ट्रेलिया न पृथक अतिरिक्त, राज्या द्वारा एक सी नीति अपनान पर उह इमलण्ड से अपन सम्बन्धा में प्याप्त स्वत तता प्राप्त होने की आसा भी थी । "अ

आस्ट्रेलिया के इस सघ की स्थापना 1 जनवरी, 1901 ई को हुई। सघीय स्पवस्था सम्ब⁻धी सवधानिक व्यवस्थाएँ

आस्टेलिया के सविवान म सपीय सरकार (Commonwealth Govern ment) की प्रांत्स्या का स्पट्ट उल्लेख किया गया है और होप शक्तिया राज्या की प्रदान की गयी है। उन्ह अपने क्षेत्र म प्रयान्त स्वत नता प्राप्त है।

सधीय सरकार को प्रदान द्यक्तिया³⁵ म सं कुछ पर उमे पूण अधिकार प्राप्त हुं जैस—सैनिक एव नोसिक मामले, मुद्रा (connage), त्रात्ति व्यवस्था, एव सथ का सुपासन आदि । सिवधान में कुछ समवर्ती बक्तियों (Concurrent powers) की मी व्यवस्था है, जस—विद्यी एव अत राज्यीय व्यापार, कापीराइट डाक तार, विवाह, सकाक, वक व्याधार, बीमा, आदि । सथ के निर्माण के पूज से ही यह दाकियाँ राज्या का प्राप्त थी । धारा 5 1 म कुछ ऐसी दाक्तिया का भी उल्लेख है जो राज्यों का पहले से प्राप्त नहीं थी । यह दिक्तिया ससद वा एकमान क्षेत्राधिकार हैं । अपुट्वेद 5 1 में उल्लिखत कोन विषय वाज्य के सविद्यान की वारा 9 1 से मिलते हैं । सचीय सरकार को राष्ट्रीय महत्व के विषय प्रदान किये पये हा का प्रयुक्त एवं समुक्त राज्य अमेरिका की तुलना म आस्ट्रेलिया के सचीय द्यासन को अधिक व्यापक चित्रा प्राप्त है और कमाडा की सधीय सुनी की अपका वह अधिव पूण भी है ।

जास्ट्रेलिया म शक्तिया के विमाजन पर व्यक्तिनादी विचारा का प्रमान स्पष्ट है। अधिकाश सर्विधान निर्माता सम्पत्तिशाली वग के थे। उनम से अनक चरागाहा के स्वामी एवं ध्यापारी भी थे। अब कनाडा के सर्विधान के शक्ति विभाजन को स्वी-

³³ Finer H op cit, p 167

³⁴ Ibid

³⁵ Section 51 of the Australian Commonwealth Constitution

बार गरना उन र जिए सम्बन नहीं या। आग्नुनिया न महियान र निमाण नसमय यहीं रे अंतर व्यक्ति 'राज्या र अधिनाग को धारणा अगिरवाग रगत थे और अमेरिकी इतिहास स तर ज्या बेरणा बाल करते थे। ³⁸

अविशिष्ट गतियाँ मानुष्त राज्य जमितना एव हिन्द्वरत्तण्ड नी मीति आर्न्टु-तिया म भी राज्या म निहित्त हैं। जबित्तण्ट शतिया म विशा, रृषि, रत-नारयान, स्वास्त्य यन पुनिस राज्या री रहें महत्त्रा-गतन, शराबदादी आदि विषय आते हैं। आस्ट्रेतिया म शक्ति विमादा न राष्ट्रा ह टीन विषयीत है।

राज्या र अपा जनग-जनम सिप्तधार है और व उन्ह सनाधित गर सकत हैं। राज्या र मजनरा नी निर्मुत प्राजा ज्ञारा मधीय सरकार नी सहमति या स्यो रृति लिए बिना नी जाती है। सधीय सरनार ना राज्या ज्ञारा निर्मित विधिया के सायम म हस्तरोप का नाज अधिकार प्राप्त नहीं है। अस्ट्रेनिया का सिध्यान नक्षा में ने सिविधान नी प्रांति त्रिटिन ससद ज्ञारा सनाधित नहीं किया जाता जिल्ह सधीय ससद (Parliament of the Commonwealth) ज्ञारा सनाधित एवं आस्ट्रेलिया की जनता ज्ञारा जनमत समझ (Referendum) का माध्यम स अनुमादित किया जाता है।

संघीय संसद ने हो सदन हैं । सीनट (Senate) का उक्च सदन और प्रतिनिधि सदन (House of Representatives) वा निम्न या प्रयम सदन वहत हैं। सीनट क सदस्या का बायकाल छ, वय है। आपे सदस्य प्रति तीन वय बाद अवकाण प्रहण कर सेत हैं। भारम्म म सीनट म प्रत्येश राज्य द्वारा छ सदस्य भेज जात थे। 1948 ई म प्रति राज्य के प्रतिनिधिया की सन्या बढाकर दस कर दी गयी है। अत सीनट की कुल सदस्य-सम्या 60 है। सभी सदस्य समानुपातिर प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार चुने जात हैं । इसस अल्पसरयना का उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है । प्रत्यक राज्य को एक निवाचन क्षेत्र के रूप न परिणत कर दिया जाता है और दस सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर जनता द्वारा निवाचित किये जात हैं। अमरिकी सीनट की नांति ही आस्ट्रलिया की सीनट म नी राज्या को समान प्रति निधिरय प्राप्त है। सीनट का प्रतिनिधि सदन के समान ही साधारण विधेयका के सम्बाध म अधिकार प्राप्त है। वित्त विधेयक प्रतिनिधि सदन म ही सवप्रयम प्रस्तुत किया जाता है । अमरिकी सीनेट की भौति ही आस्ट्रेलिया की सीनट को वित्त विघेयका को आमूलचूल रूप म अस्वीकृत करने, सद्योधित करने, नये कर प्रस्तावित करने या प्रस्तावित धन राशिया हो कम करने या उनम वृद्धि करने का अधिकार प्राप्त है। यदि प्रतिनिधि सदन द्वारा पारित कोई विधेयक तीन माह के अंतराल मं दो दार सीनट द्वारा अस्वीकृत किया जाता है तो गवनर-जनरल को दोना सदनो का विपरित करके नवीन निर्वाचन का आदेश देने का अधिकार है। यदि नव निर्वाचित संघीय ससद के दोना सदना में भी मतभेद रहता है वो गवनर जनरल दोना सदनों की सयुक्त बठक आहुत कर सकता है और सयुक्त सदन द्वारा बहुमत से पारित होने पर

36 Crisp Parliamentary Government of Australia, pp 11 and 25 28

गवनर-जनरल द्वारा स्वीकृत होने पर विवादास्पद विषेयक विधि बनता है। आस्ट्रे-लिया के सविधान निर्माताओं को सीनट से दो कतव्या की अपेक्षा थी। प्रथम, सीनेट सदोधन करने वाले सदन के दाखित्वा का पूण कर। दितीय, राज्या के हितो की रक्षा की आद्या भी सीनेट से की गयी थी। इन कार्यों को सीनेट सम्पादित नहीं कर सकी है। बाइस का कपन है कि "जिन आद्याओं से सीनेट की रचना की गयी थी वे वाद की घटनाओं से गलत प्रमाणित हुई है। यह राज्यों के हिता की रक्षा नहीं कर सकी है।" अमेरिकी सीनेट की मालि उमे निर्मुक्त एवं सिय्या के सम्बन्ध में अजिकार नहीं है। हैनरी टनर के अनुसार प्रतिनिधि सदन द्वारा धीष्टता में पारित विधेयकों को रोकने एवं राष्ट्रीय एकता की इंटिट से महत्वपूण विवेयक पारित करने में सीनेट असफल रही है।

सघीय कायपालिका निक्त सपरिषद् गवनर जनरल मे निहित है। गवनर-जनरल महारानी का प्रतिनिधि एव नाममान का अध्यक्ष एव कायपालिका है। मिन-परिषद वास्तविक कायपालिका है जो सघीय ससद के प्रति उत्तरदायी होती है। सघीय मिनमण्डल का नेता प्रधानमानी होता है।

सिवधान द्वारा सधीय यायपालिका की भी स्थापना की गयी है। आस्ट्रेलिया का उच्च यायालय राज्य का सर्वोच्च सधीय यायालय है। उच्च न्यायालय की को अरेरिकी सर्वोच्च यायालय की माति सिवधान की व्यारण करने एव सच सरकार और
राज्या तया राज्या के पारस्परिक विवादा के सम्ब्योग में मिलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
उच्च न्यायालय की सधीय कमचारियों के विरुद्ध आदेश पत्र (writs) जारी करने का
अधिकार है। उच्च के सर्वोच्च यायालयों या अत राज्यीय आयोग के ऐसे तिणयों
के विरुद्ध अपील भी की जा सकती है जिनका सम्ब व किसी विधि से होता है।
इन मानला में उच्च को विधियों से सम्ब्रिध होता है। इन्सरणीय है कि अमिरिकी
सर्वोच्च यायालय में राज्य की विधियों से सम्ब्रिध तिणयों के विरुद्ध अपील आस्ट्रेलिया के सर्वोच्च यायालय की माति नहीं की जा सकती । आस्ट्रेलिया की सधीय
ससद को उच्च यायालय की मीति नहीं की जा सकती । आस्ट्रेलिया की सधीय
ससद को उच्च यायालय की मीति नहीं की जा सकती । आस्ट्रेलिया की सधीय
ससद को उच्च यायालय की मीति नहीं की जा सकती । भी अधिकार है।
उच्च यायालय के सीलक क्षेत्राधिकार को बढाने का भी अधिकार है।
वच्च स्थायालय के सदाचरण पय त इस पत्र पत्र क्षा करते रहते है। अयोग्यता
एवं द्व्यवहार के अपराच के लिए उन पर महाभियोग लगाया जा सकती है।

स्द्राग³ के अनुसार आस्ट्रेलिया राज्य की सघीय प्रणाली सच्ची है। राज्या को अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त है। प्रत्येक को सीनेट में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। बनाडा की मांति राज्या के गवनरों की नियुक्ति सघीय सरकार द्वारा नहीं की जाती अपितु नाचन द्वारा राज्यों के मिन्नया के पर्याग्ध पर प्रत्येक राज्य का गवनर नियुक्त किया जाता है। संयुक्त राज्य अमरिका के राज्यों की माति गवनर निवाधित नहीं होत है। सिवधान म यह व्यवस्था भी है नि यदि कोई शब्द राज्य स मन्दिपत रिमो विषय पर मधीय मगद द्वारा विधिनिनमाण म रिमी प्रशास का मोरा पाहता है तो उन ऐमी सहायता उपत्र प होशी। क्कीकरण की प्रवत्ति

आम्ट्रेनिया र मित्रधान ना निमाण आधृनिक युव ने मिय-नान म हुआ या। राध्य नगरा महान मकारा महाद्याय द्याया को धारण नरन का प्रयत्न कर रहा था। आम्ट्रेनिया म मी उपना प्रभाव पडा और सधीय तूची म नीज गति स विद्धि हुई है। यह बद्धि मयुक राज्य अविरक्ता ही मौति चायिर व्याच्या (judicial interpretation) वा परिणाम है। इसके अविरिक्त, मुख्या की समस्या तथा सामा-जिक सवाजा नी बद्धि र नराज मी सथीय सासन की सक्तिया म वृद्धि हुई है। अभिन्या ने भीति मधीय सासन एय राज्या के अवाधिकार र प्रदन वर आस्ट्रेनिया म भीती मुनियार उत्पन्न हात रह है।

आस्टिनिया म सुरमा ने प्रदन को लकर तील विवाद क्ला है। अवेरिका एव कनाडा की नुलना म मुरक्षा की समस्या ने आस्ट्रेलिया की केन्द्रीय सरकार की शिलिया में अत्यधिक बढ़ि की है।

कनाडा3 का सघ

कताडा या यतमान सविधान एव शासन उन विभिन्न एतिहानिक गत्तिया का स्पामाधिन परिणाम है जिनक फलस्वरूप त्रिटेश उत्तरी अमरिका एक राष्ट्र बना है। 1 जुलाई, 1867 इ का त्रिटिश सबद द्वारा परित त्रिटिश नाय अमिरिका एक्ट (The British North America Act, 1867) पानिन किया गया था। यही करावत का वत्रान सविधान है। इस सविधान द्वारा बनाडा य स्वीय व्यवस्था की स्थापना की गयी है।

वनाडा के संघीय शासन की स्थापना म बाह्य शक्तियों की अपेक्षा आ तरिक शक्तिया अधिक सनिय रही थीं पर तु संघीय शासन के स्वरूप के निधारण म आ तरिक एवं बाह्य दाना तरनों ने समान रूप से मीग दिया है। उत्तरी (नाय) बिटिस अमें

³⁸ कताण प्रारम्भ म फेव उपनिवेश या जिसकी स्थापना 1608 ई म हुई थी। अग्रजो न 1759 60 ई म इस पर आिषण्य स्थापित किया और 1763 ई को परिस सिष द्वारा य विजित क्षेत्र पूरी तरह ब्रिटिश सासन के जत्यलं आ ग्रंग थे। अमेरिकी स्वारा य सिष्मकाल म सामाज्य की एवता के सम्पर्का में से अनक ने कनावा में आग्रय विवाद या। 1791 ई म कनाड़ा एवट के द्वारा उत्तरी क्लाड़ा एवं दक्षिणी या निचल (Lower) बनाड़ा (फक्र प्रदेश) नामक दो प्रारा तना दिने 'में। कोश्यर कनाड़ा की व्यवस्थापिका म से क्लाओं को वाहुत्य या जबकि कायापिका में सामें क्षेत्र थे। एक्तस्वरूप राजीव स्तर पर द्वेग उत्तर्भ हो गया और विद्वाह फूट पड़ा। इस स्थित पर प्रतिवेदन (report) देन क तिए लॉड डरहम की नियुक्ति की गयी थी।

रिका के उपनिवेशों के मध्य सघ की घारणा अभेरिकी उपनिवेशों की स्वतन्त्रता-सग्राम के समय ही ज म ले जुकी थी पर तु ऐसी घारणा के फलीभूत होने के लिए जिस सह-यागी प्रयत्न की आवश्यक्ता थी उसका दीघकाल तक उपनिवेशा में अभाव बना रहा। लॉड डरहम (Lord Durham) ने अपने प्रतिवेदन में उत्तरी अमेरिकी उपनिवेशों के सब का सुसाव निम्न शब्दों में दिया है

"मने देखा है कि एक राज्य के हृदय म दो राष्ट्र सघपरत है। यह सिद्धातों का समय न होकर जातियों का समय था। मैंने यह अनुभव किया है कि विभिन्ना या सस्वाओं के द्वारा सुधार के प्रयत्न के कही अधिक उचित यह होगा कि उस प्राण-पातक शानृता का पहले अन किया जायें जो निचले कनाडा को फेच एवं अग्रेजी दो विरोधी मागों में विभाजित किये हुए हैं।

अय प्रातो की भी स्थित अच्छी नहीं थी। कनाटा के उत्तरी भाग में अप्रेण जाति एव दक्षिणी भाग में फच जाति के व्यक्ति निवास करते थे। लॉड डरहम ने अपने प्रतिवदन में इन दोना भागा के सब के निर्माण एव उत्तरदायी शासन की स्थापना का मुक्ताव दिया था। दोनो भागों ने एक्किरण के फलस्वरूप ही राष्ट्र-जातिगत विदेष का अत एव उत्तरदायी शासन की स्थापना सम्मव हो सक्ती थी। दोनो राष्ट्रजातियों की पुषक संस्कृतियां ने उत्तरदायी शासन को असम्मव बना दिया। उत्तरी कनाडा के निवासियों ने जनसरया की हिन्द से प्रतिनिधित्व की माग प्रस्तुत की थी। इससे राजनीतिक संतुलन के विग्रड जाने की पूण सम्मावना उत्पन हो गयी थी क्यांकि दक्षिणी भागा में फेच प्रापामायी अल्पमत में थे। अत क्रेंच माया मायी यह अनुमव करते लग थे कि वे अपने को एक पृथक राजनीतिक इनाई के रूप स सम शासन के अतगत हो कायम रन्य सक्ते है। अत डरहम रिपोट (1841 ई) के द्वारा प्रस्तावित एकारक संविधान का असफल हो जाना स्वामाविक यो और 1860 ई तक वह असफल भी हो कुका था।

इसके अतिरिक्त, उत्तरी अमेरिका के ब्रिटिश उपनिवधा को अमेरिका साम्राज्य के आरमण का मी त्रय था। 1775 ई और 1812 ई व अमेरिका सना न कताडा की सीमाओं का अतिक्रमण किया था। फलत यह मावना बलवती होती जा रही थी कि उपनिवेदों द्वारा सच बना कर ही अपनी रक्षा की जा मक्ती है। इसने अतिरिक्त आर्थिक कारणा ने सी सुच के निमाण स याण दिया था।

उपनिवेद्यों के समक्ष अनंक आर्थिक ममस्याए थी। नाविक विधिया (Navigational laws) एव विनेष चुनी व्यवस्थाना के नारण 1840 50 इ वे वर्षों म उत्सन समस्याना न सप के निमाण की नावना की प्यान्न वल प्रदान हिया। नवीन ओद्योगिर प्रगति में उत्पन ममस्याथा का ममाधान किनी भी उपनिवदा वे सामित स्रोता एव जिब्दिसत यातायात की प्रणाली के नाग्य सम्मव नहीं ना। इन सण्य परिस्थितिया के सहब परिणामस्यस्थ सधीय शानन म निमाण पर चल दिया समा, और 1864 ई के वसन्त म बहु बनाहा की तत्यालीन राजनीति गा

प्रश्त बन गया था। इस सम्बाध म नीवीस्क्रीशिया (Novo Scotia) के प्रधानमात्री डॉ चाल्स ट्रमूपर (Dr Charles Tupper) ने पहल की और अपने प्राप्त की व्यव म्पापिका थे न्यू बु सनिक (New Brunshwick) एन प्रिस एडवड द्वीप (Prince Edward Islands) के प्रतिनिधियों से संघीय शासन के निर्माण हेतु वार्ता के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का एक प्रम्नाव प्रस्तुत किया। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप 10 अक्टूबर, 1964 ई को क्यूबेक (Quebec) म कनाडा के इतिहास का युगा तरकारी मम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन म चारलोटीटाउन (Charlottetown) में हुए पहले सम्मे नन म स्वीकृत संघीय शासन की स्थापना सम्बंधी मूल सिद्धान्त नी स्वीकार कर लिया गया । न्यूवंक के सम्मेलन में 18 दिन में 72 प्रस्ताव प्रतिनिधिया द्वारा स्वी-कार किये गये। यही प्रस्ताव ब्रिटिश नॉय अमेरिका एक्ट, 1867 ई के आधार वने। इन प्रस्तावा को क्लाडा के विधानमण्डल द्वारा तो स्वीकार कर लिया गया परतु तटीय प्राप्ता मे इनका बडा विरोध हुआ था। इस पर दिटिश सरकार द्वारा नोवी-स्कोशिया, न्यू बुमिविक एव बनाडा के प्रतिनिधियों का सम्मेलन संदन म आयोजित किया गया। फलस्वरूप ब्रिटिस ससद द्वारा त्रिटिश नॉय अमेरिका एक्ट, 1867 ई पारित किया गया जो 1 जुलाई, 1867 ई से प्रमावकारी हुआ। कनाडा के बोर्मिनयन या उपनिवेश (Dominion of Canada) में इस समय ओ टोरियो (Ontorio) और क्यूवक (Quebec), यू मुसविक (New Brunswick), नोबोस्कोशिया (Novo Scotia) नामक चार प्रान्त थे। कनाडा की क्यूबेक एव ओ टीरियो नामक दो प्राप्ता में विमाजित कर दिया गया था। रूपाट द्वीप (Ruperts Island) एव उत्तरी पहिचमी क्षेत्र और मेनीटोबा (Manitoba) 1870 मे, ब्रिटिश कोलम्बिया (British Columbia) 1871 ई में, प्रिस एडवड द्वीप (Prince Edward Island) 1873 ई म कनाडा के सद्य में शामिल हुए थे। 1905 ई म परिचमी क्षेत्र को अल्बर्टा (Alberta) एव सस्केचवा (Saskatchewan) नामक प्रान्तो म विभाजित कर दिया गया । 1949 ई म यू फाउण्डलैण्ड (New Foundland) के शामिल होने पर कनाडा म दस प्राप्त हो गये है। कनाडा के संघात्मक शासन का स्वरूप

कनाडा के सविधान-- त्रिटिश नाथ अमेरिका एक्ट, 1867 ई-एव अप परवर्ती सशाधन करने वाले विधेयको में निम्नलिखित विशेषताएँ पायी जाती हैं

(1) डोमिनियन एव प्रातीय विधानमण्डला के मध्य श्रक्तियों का स्पष्ट विमाजन चार मागो म किया गया है। प्रथम माग म डोमिनियन ससद के क्षेत्रा-धिकार म आने वाले विषया का उल्लेख है (Section 91)। द्वितीय माग म प्रान्ती के क्षेत्र के विषया का उल्लेख हैं (Section 92) । तृतीय माम में उन धालियों का जल्लेख है जिनके सम्बाध म डोमिनियन एव प्रातीय दोनो ही व्यवस्थापिकाओं को विधि निर्माण का अधिकार है। चौथे भाग का सम्बंध शिक्षा से हैं (Section 93)। अविशिष्ट शक्तियां डोमिनियन (के द्रीय या संघीय) शासन नो प्रदान की गयी हैं।

- (2) डोमिनियन (संघीय) एव प्रातो की व्यवस्थापिकाएँ पृथक-पृथक है और दोना म से किसी को भी विषय-सुचियो म परिवतन करने का अधिकार नही है ।
- (3) न्यायालय को आतीय एव डोमिनियन विधियों की सर्विधान की धाराओं के विपरीत होने या के द्रीय एव शातीय शासनों के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करने के आधार पर अवैधानिक घोषित करने का अधिकार है। स्पष्ट है कि कनाडा के सर्विधान में सर्वधानिक सप्रमुता के सिद्धान को मा यता दो गयी है।

प्रो केनेडि के अनुसार कनाडा की संघीय व्यवस्था की चार प्रमुख विशेषताएँ हैं (1) कनाडा की डोमिनियन (संघीय) व्यवस्थापिका को साम्राज्यीय या प्रातो की ध्यवस्थापिकाओं से अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। (2) प्रातीय व्यवस्थापिकाओं को भी शक्तिया साम्राज्यीय व्यवस्थापिका द्वारा प्रदत्त नहीं हैं अपितु वे भी अपने क्षेत्र में पूण अधिकार-सम्य न है। (3) टोमिनियन संघीय संसद द्वारा प्रातीय व्यवस्थापिकाओं को अधिकार-सम्य नहीं किये गये हैं। (4) प्राप्त स्वतत्त एव पूण स्वायस सत्ता सम्यत हैं। राष्ट्रीय एव प्राप्तीय सरकार अपने अपने क्षेत्र भे प्रमु एव समान रूप में (coordinate) सत्ता-सम्पत्त है। स्पष्ट है कि कनाडा का सविधान स्वरूप मं संघीय है।

पर तु कनाडा के सपीय स्वरूप के सम्बंध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। कनाडा की सपीय व्यवस्था म के द्रीकरण अपेक्षाकृत अधिक है। सिवधान निर्माताओं ने सभीय शासन को अधिक शिक्ता प्रदान की है और उसे अधिक शिक्ताली बनाया है। वे समवाद के सकीण एव अमेरिकी सस्करण में विश्वास नहीं करते थे। अमेरिका में सब प्रवाद के प्रवाद के मध्य सप्रभुता सम्बंधी विवाद की चरम परिणति गृह युद्ध में सु हुई थी। कनाडा के नेताओं ने इससे शिक्षा ग्रहण की। अत क्यूबेक सम्मेलन म उप-स्थित अधिकाश नेताओं की यह हुई धारणा थी कि सच में प्रारम्भ से ही विघटनकारी प्रविचारों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। फलत सविधान में सप की घटक इकाइया की शिक्ता का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है और अवशिष्ट शिक्ता सपीय सरकार को प्रवात की मथी है। सर जान में क्वीनल्ड (Str John MacDonald) नामक सविधान निर्माता के निम्म वाक्य इस सम्बंध में महस्वपुण हैं

"परिसध का सच्चा निद्धात यह है कि सामा य सरकार (General Government) को सत्रभुता के सभी सिद्धात व शक्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए और

³⁹ Kennedy W P M The Constitution of Canada Ch XXIII Lord Haldane held the view that Canada was not a true Federation because the British North America Act, 1867, created not only a new common government but also new provincial governments whose powers were confined exclusively to a list of subjects enu merated in section 92 of the Act —Wheare K C opent, p 197 Prof Wheare calls the Canadian Constitution a quasi for constitution, p 19

अधीनस्य सरकारा (Subordinate Governments) के हायो म स्पष्टत प्रदत्त के अतिरिक्त अप कार्द्र शक्ति नहीं होनी चाहिए। अत हमारी व्यवस्था शिक्त शाली के द्रीय शासन और विधानमण्डल तथा स्थानीय मामला के लिए लघु विधान मण्डला की विकर्ष द्रत व्यवस्था होनी चाहिए।"

इसके अतिरिक्त, कनाडा के सविधान की निम्नलिखित सवैधानिक व्यवस्थाएँ

के द्रीकरण की परिचायक है

(1) प्राप्तों को प्रवक्त शक्तियाँ स्थानीय महत्व की है। महत्वपूण शक्तिया ने श्रीय शासन को प्रदान की गयी है। समवर्ती सूची ने केवल दो ही विषय थे—इपि एवं उदजन। प्राप्ता को ऋण लेने का भी अविकार दिया गया है। प्राप्ता के अप स्रोत अपयाप्त थे अत उनके लिए डोमिनियन (मधीय) श्रासन से आर्थिक अनुवान की व्यवस्था की गयी है।

(2) घारा 91 (Section 91) के द्वारा राष्ट्रीय सबद को स्पष्ट रूप से कनाड़ा की झालि एवं व्यवस्था तथा मुझासन के लिए प्रातों को प्रदत्त शक्तियों सिहत सभी विषयों में विधि निर्माण का अधिकार दिया गया है। युद्ध की अवस्था म के प्रीय झासन को प्रातीय विषयों में भी विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है।

(3) डोमिनियन शासन को प्रात्तीय विचानमण्डल द्वारा पारित किसी मी विधेयक को एक वय के अतराल में अस्वीकार करने का अदिकार प्रदान किया

गया है।

(4) प्रा तो म समी महत्वपूष न्यायिक नियुक्तियो की शक्ति डोमिनियन

शासन के हाथों में है।

(5) डोमिनियन (सपीय) द्यासन को प्रातों के उप-राज्यपाला को नियुक्त एवं पदच्युत करने की शक्ति प्राप्त है। प्रातीय उप-राज्यपालों को किसी प्रातीय विषेयक को स्वीकृत न करने के आदेश देने का अधिकार डोमिनियम सासन को है। गवनर-जनरस को उन विभेयकों को जिल्हें वह उचित न समस्ने, अस्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त है।

(6) सीनेट के सदस्य डोमिनियन सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं वर्षि सभी प्रात्तो को सीनेट के अमेरिकी सीनेट की माति सभान प्रतिनिधित्व प्रदान किया

गया है।

कताड़ा के सविधान के सम्बाध में विधित मत ब्यक्त किये गये हैं। प्रो के सी ह्वीधरे का मत है कि "डांमिनियन द्वासन को प्रा तीय सूची के विषया से सम्बीधत विधि को अस्वीकृत करने की शक्ति केर के द्रीकरण की व्यवस्था की गयी है। गया सासन के ने द्रीवरण या एकीकरण की प्रवत्ति का इसते बधिक अप कोई अहन ही सकता है " स्मरणीय है कि कनाड़ा के सविधान म सधीय सिद्धात को पूरी तरह से उपेसा नहीं को गयी है। ब्रिप्त म चस महत्वपुण स्थान प्राप्त है। 'यदि हम केवत सविधान तक ही धीमित रह तो यह निषय करना कठिन है कि कनाड़ा के सविधान

को सघीय सनिधान या पर्याप्त सघीय प्रवित्तयो से युक्त एकात्मक सिवधान कहा जाय । "उसे सघीय सनिधान कहना सघीय सिद्धान्त के साथ व याय करना होगा । अत में कनाडा को बद्ध सघीय सनिधान कहना पसन्द कहँगा।"⁴⁰

प्रो सी एफ स्ट्राम काडा के सिवान को संशोधित सघवाद की सजा देते हैं। उनके अनुतार कनाडा का सिवधान समुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलण्ड एवं आस्ट्रेलिया के सिवधाना की अपक्षा कम संधीय है क्यों कि इन तीनों सिवियानों में अव- शिष्ट शक्तिया राज्यों को प्रवान की गयी है जब कि कनाडा में ठीक इसके विपरीत व्यवस्था है। इसी कारण कनाडा को संशोधित संधवाद का जदाहरण कहा जाती है। काडा को पर हो अर्थों में राज्य नहीं है। वं प्रात कहें जाते हैं जो इसलेण्ड के स्थानीय अधिकारियों एवं दक्षिणी अफीका के बार प्रातों से कहीं अधिक शक्तिका के बार प्रातों से कहीं विधिक शक्तिका के बार प्रातों से कहीं विधिक शक्तिका है। कनाडा का डोमिनियन पूणत संधीय राज्य नहीं है। द ननाडा के सिवान पूणत संधीय राज्य नहीं है। कनाडा के सिवान प्रात्त से कि कि विपरीत है। कनाडा के सिवान में प्रात्त से ठीक विपरीत है। कनाडा के सर्वोच्च यायालय को सिवान को व्यवस्था का कोई अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त उल्लिखित एकात्मक प्रवृत्तिया का भी स्ट्राग ने उल्लेख किया है।

कताडा के सधीय सविधान म केन्द्रीकरण की अनेक उपर्यक्त प्रवृत्तियों के होते हुए भी उसका विकास विपरीत दिशा म हुआ है । प्रो ह्वीयरे ने सविधान क व्याव-हारिक रूप को सविधान की विधि से अधिक महत्व दिया है। किसी देश का सविधान संघीय हो सकता है लेकिन यह सम्भव है कि सविधान का व्यावहारिक रूप ऐसा हो कि वहा की सरकार संघीय न हो। अत हीयर का मत है कि विधिक इप्टिस कनाडा का सविधान अद्ध संघीय (quasi federal) होते हुए भी व्यवहार म संघीय है। दूसरे शब्दों में, कनाड़ा का सविधान संघीय नहीं है पर त उसका शासन संघीय है। 18 इसका यह अथ है कि सविधान की एकात्मक प्रवत्तिया का व्यवहार मे इस प्रकार प्रयोग किया गया है कि प्रात्तों को व्यापक राजनीतिक एवं विधिक शक्तिया प्राप्त हा गयी है। अपने क्षेत्र म प्रान्त पुणरूपण स्वायत्त सत्ता-सम्पन हैं। सघीय शासन द्वारा प्रान्तीय विधिया को स्वीकृत करन की शक्ति का यदाकदा केवल उ ही विधिया के स दम म प्रयोग किया जाता है जो कनाडा के हितो के विरुद्ध होती हैं। अब प्राता के उप-राज्यपाल के द्रीय शासन के उपकरण नहीं रहे हैं। डोमिनियन शासन द्वारा उनकी नियुक्ति केंद्र एव प्राता म सधीय कडी का ही नेवल प्रमाण है। एक बार नियक्ति हो जान के बाद उप राज्यपाल किन्ही अर्थों म संघीय सरकार के अधीन नहीं होता । व्यवहार म बनाडा के प्रान्त जाज सबुक्त राज्य जमरिका के राज्या स कही

⁴⁰ Wheare, k. C. Federal Government, 1963, p. 19 41 Strong, C. F. Modern Political Constitutions, p. 120

⁴² Wheare, L. C op at, p 21

अधिक शक्तिया का प्रयाग करते हैं। इस स्थिति के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं

(1) ब्रिटिश नॉथ अमेरिका एक्ट की केवल धाराओं के अध्ययन से कनाडा की सघीय व्यवस्था का वडा गलत चित्र उपस्थित होता है। एक्ट द्वारा सिद्धातत सभी सघीय शक्तियाँ गवनर-जनरल मे अधिष्ठित की गयी हैं पर तु वास्तविक सत्ता का प्रयोग मि त्रमण्डल करता है जिसका अधिनियम म कही कोई उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार डोमिनियन सरकार को प्रातीय विधेयको पर नियेधाविकार प्राप्त है। नेकिन सर्वियान के सिद्धात व ब्यवहार के भेद को इस व्यवस्था के सदभ म देखकर चिकत रह जाना पडता है। विधिक दृष्टि से इस निर्पेधाधिकार पर कोई प्रतिबाध नहीं है। डोमिनियन सरकार ने इस अधिकार का प्रयोग अवैधानिक विधेयक क विरुद्ध ही नहीं अपित ऐसे विधेयकों के विरुद्ध भी किया है जो उसे अप्रिय एवं अस्वीकार थे। प्रातीय विधेयका को संघीय शासन द्वारा अस्वीकृत करने के आधार समय-समय पर मिन मिन रहे है। यह भी नहीं कहाजा सकता है कि अब इसका प्रयोग नहीं होगा । पर तु इस सम्बाध मे रोविल सिरोस प्रतिवेदन के मत को उदघत करना समी चीन है--"हम यह सोचने के लिए बाध्य हैं कि निपेधाधिकार का प्रयोग इतना स्वत त्रतापूर्वक अव नही किया जायेगा जितनी स्वत त्रतापूर्वक परिसय के प्रथम 30 वर्षों में इसका प्रयोग किया गया है। लेकिन निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।" कनाडाम विधायी सप्रभुता 1867 ई की अपेक्षा आज अधिक माय है। प्रीवी काउसिल के निषयों ने प्रातीय विधानमण्डला की सप्रमुता को स्यापित करने म विशेष योग दिया है।

(2) राजनीतिक अधिकारियों के हृष्टिकोण का भी प्रमाव सिंवधान के कियारमक रूप पर पड़ा है। सिंवधान के प्रारम्भिक काल स सर जॉन सब्होनस्ड प्रमुख राजनीतिन थे। वे प्रातीय विधानमण्डलों को दितीय श्रंणी का विधानमण्डल मानते थे और प्रातीय उप-राज्यपालों को भी डोमिनियन धासत द्वारा मनोनीत अधिकारी मानते थे। इनका काम कतव्यपरायण सेवका की भीति डोमिनियन सरकार के हिता की रसा करना था। मवडोनव्ड ने ही प्रातीय विधेयका को अस्थिकृत करने की व्यवस्था प्रारम्भ की थी। सिवधान के प्रथम दशक से ही संधीय खासन द्वारा 29 प्रातीय विधेयकों को अस्थिकृत करने की व्यवस्था प्रारम्भ की थी। सिवधान के प्रथम दशक से ही संधीय खासन द्वारा 29 प्रातीय विधेयकों को अस्थिकृत करने की व्यवस्था प्रारम की थी। सिवधान के प्रथम दशक से ही संधीय खासन द्वारा 29 प्रातीय विधेयकों को अस्थिकृत करने की व्यवस्था प्रारम प्रारम प्रारम प्रारम की धी। सिवधान के स्थान प्रया था। उदारवादी सल ने तता ओवीय मोवेट (Olner Mowat) थे। उचने दोधिनियन धासन द्वारा प्रातीय विधेयका की अस्थिकृत करने की शांतिक का उच विरोध किया। उदारवादिया ने सिवधान की सीमा के अन्तात प्रातीय स्वायसता की सौंग की थी। के दीकरण की नीति के विरद्ध असतीय सासह दुना। उसने के दीवरण की प्रवत्ता पर साम उसने का स्वता प्रापता का साम विधान की सीमा का निया था। साम के दीवरच असी साम प्रात्ता उसने के दीवरण की प्रवत्ता हुना। उसने के दीवरच का निया था। साम के प्रतान की सीमा वारा प्रसान प्रतान की का निया था। साम के प्रतान की उत्तारन सी साम प्रतान की कम निया था। साम के प्रतान की उत्तारन सी साम प्रतान को कम निया था।

किसी भी अधिकार का परित्याय नहीं किया और न इनको निरकुश ही माना । उस समय से प्रातीय विधेयकों को अस्वीकृत करने के सम्बन्ध म सधीय सासन द्वारा साव धानी अवस्य बरती जाने लगी है। अब कभी-कभी ही प्रातीय विधेयका का टामिनियन सासन द्वारा अस्वीकृत किया जाता है। सत्य तो यह है कि अब प्रात्तीय विधानमण्डल की भूतो एव दोपों का निर्णायक मतदाता होता है न कि डोमिनियन शासन।

(3) तमश विकसित एव स्थापित ससदीय श्वासन सम्बापी अमिसमयो ने भी कनाडा की सधीय व्यवस्था को प्रभावित किया है। सविधान के अनुसार कनाडा के गवनर-जनरस द्वारा ही प्रातीय उप राज्यपालों को नियुक्ति की जाती है और उप-राज्यपाल मिनयों को नियुक्ति करता है। लेकिन इस सम्बाध में इस अमिसमय का विकास हुआ है कि प्रातीय उप राज्यपाल को प्रातीय व्यवस्थापिका के वहुमत दल में से ही मिनया की नियुक्ति करनी एडती है। डोमिनयन शासन के द्वारा जनता के इस प्रतिनिधियों को मायता देना स्वामाविक है। जनता के निष्य की उपेक्षा करना उनके लिए सम्मव नही है। इसी प्रकार, डोमिनियन सरकार को प्रात के उच्च प्रतात के लिए सम्मव नहीं है। इसी प्रकार, डोमिनियन सरकार को प्रात के उच्च सात के लिए सम्मव नहीं है। इसी प्रकार, डोमिनियन सरकार को प्रात के उच्च सात के लिए सम्मव हो है। इसी प्रकार, डोमिनियन सरकार को प्रत के उच्च मायत के विकार हो। उपमोग किया है और यायाधीकों के पद पर दलीय हिट्ट से नियुक्तिया नहीं की है।

बत ह्वीयरे का मत है कि बनाडा राजनीतिक रूप से संघीय है और कनाडा में जिस किसी डोमिनियन शासन ने संविधान के एकारमक तत्वों को संघीय तत्वों की कीमत पर स्थापित करने का प्रयत्न किया है वह सफल नहीं हो सका है 162 ह्वीयरेने कनाडा की संघीय व्यवस्था को ध्यान में रखकर कहा है कि 'कनाडा का सविधान विदिक हेटि से अद संघीय होते हुए भी व्यवहार में संघीय है।'

पर तु सत्य इसके विपरीत है। ह्वीबरे के मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता । ह्वीयरे के मत को ब्यक्त हुए काफी समय व्यतित हो चुका है। कता ब्रा के सिवधान का निर्माण जिस समय हुआ था उस समय पुलिस राज्य की धारणा माय यी। अब तो लोक कत्याणकारी राज्य का आदश स्तुत्य एव माय है। सामाजिक कत्याण की अनेक गोजनाएँ राज्य का अधम दायित्व वन गयी है। प्रा तीय शासना में ऐसी अनेक गोजनाओं को प्रारम्भ किया है। अस तोपजनक वितीय स्थिति पे कारण प्रातीय शासना को के द्वीय सरकार पर धन के निष् अधिकाधिक निमर रहना पडता है। फलस्वरूप में देव निमर हो। सत्तार प्रातीय शासना की के द्वीय सरकार का प्रातीय सरकारों पर निय येण मी वह ना है। एस पी अय्यर के अनुसार, "यदापि कनावा में के द्र एव राज्य के मध्य मध्यना की सहयोगपूर सम्बच्धों की सजा दी जाती है पर तु वह सजा उचित नहीं है। एस पी

⁴³ Canada is politically federal and that no Dominism ("") ment which attempt to stress the unitary elements \$\(\); \(\) \(

स्विस परिसध

स्विस परिसय (Swiss Confederation) विश्व के वतमान सघीय राज्यों में प्राचीनतम सघ है। स्विटजरलैण्ड को परिसय (Confederation) कहा जाता है पर सु स्वाम के अनुसार "यदि परिसय का अब सुहढ के द्वीय सत्ताहीन राज्यों के ढीले खाले सघ से है तो अब वह (स्विटजरसण्ड) परिसय न होकर एक सच्चा सपीय राज्य है। पर सु वह सदव ही ऐसा नहीं या।" 45

स्विस गणराज्य मे 22 के टन है। के टन स्विस परिसंघ की घटक इकाइयों हैं। इनमें से तीन के टना—अ टरबाल्डन, बेसता एव ऐपनजीत —के विमाजित होंगे से 6 अब के टनो का निर्माण हुआ है। प्रत्येक अब के टन अपने मूल अबनाग से पूण स्वत के होता है। अब-के टन एव पूण के टन म दो अ चर है। प्रयान, अब-के टन दिवत संग्रिय समा के उच्च सदन—राज्य-परिषद (Council of States)—मे प्रतिनिधि के रूप म एक सदस्य भेजता है जबिक पूण के टन के द्वारा दो सदस्य भेजे जात हैं। दितीय, सब धानिक ससीधम के सदस्य में अब के टन का मत भी आधा ही मिना जाता है। अत यह कहना अधिक उपमुक्त होगा कि दिवस परिसंघ म 25 के टन है जिनमें 6 अब के टन का भी राष्ट्री परिसंघ के 25 के टन है जिन ते 6 अब के टन का भी राष्ट्री परिसंघ के 25 के टन है जिन ते 6 अब के टन का भी राष्ट्री परिसंघ स्वीयान, अपनी राष्ट्रीमता, अपनी विविधा, परप्पारार, रीति रिवाज, वैचारिक प्रवृत्ति एव इतिहास है।

स्विस परिसय का इतिहास काकी पुराना है। इसकी स्थापना 13थी सदी म आस्ट्रिया के प्रमुख के विरुद्ध सथय करने वाले तील जिला जिन्ह यन केट स (Forest Cantons) कहा जाता है हारा हुई थी। 1648 ई को क्स्ट्रेलिया सिंप (Treaty of Westphalia—1648) हारा इसे स्वत व राज्य मान लिया गया था और इस समय तक उसके घटक राज्यों को सख्या 13 हो चुकी थी। नयोतियन के समय तक यह सुदृढ केट्रीय सत्ताहीन राज्यों का एक डीला डाला सथ ही बना रहा। 1815 ई के यूरोपीय समक्षीत के समय म भी इसका यही ह्य विद्याना था। 1847 ई में स्विटायर एक लिया गुह-युद्ध हुआ था। रोमन क्योतिक धमानु यापी 7 केटना ने परिस्तय से पुनक होने का निक्यय किया था। इस यहमुद्ध के बाद ही 1848 ई का सविधान बना। इस सविधान हारा पुराने परिस्तप (Staatenbund)

⁴⁴ Aiyar S P Federalism and Social Change p 130 45 Article 1

⁴⁶ Strong, C F op cat, p 114

को सपीय राज्य (Bundesstaat) म परिवर्तित कर दिया गया । परिसघ क इस सिवमान को 1874 ई में भी सभीधित किया गया । सामान्य रूप म यही सिवधान इंछ परिवर्ती संशोधना सिहत स्विटजरलण्ड म आज भी विद्यमान है।

स्विटबरतंब्द को परिसप कहना ठीक नहीं है । परिसप पूर्वोटलेखानुसार राज्या का ऐसा ढीवा ढाला तथ होता है जिसम सुद्देढ के द्वीय सत्ता का अभाव होता है जीर उसे आवश्यकतानुसार विधिटत भी किया जा सकता है। इस संच्यम सिता परिसप को प्रस्तावना के निम्म वाक्य ध्यान देने योग्य है 'स्विम परिसप का मिम सम्मा को एकी कृत करने तथा स्विम रास्त्र की एकता है। इस संच्यम परिसप का मम साम को रक्षा के विस् हुँग हैं। अत स्विम रास्त्र की एकता, शक्ति एव स्वा को स्वीकार किया गया है।"

यदि यह मान भी लिया जाय कि प्रस्तावना का कोई विधिक मुख्य नहीं होता है तो भी इससे सिवधान निर्माताका की इच्छा का ज्ञान तो होता ही है । स्मरणीय है कि स्वित सविधान को स्वित जनता ने जनसव-संग्रह के द्वारा स्वीकार किया था । क्षत इससे भी परोक्ष रूप म जनता की इच्छा का ही पता चलता है। सत्य तो यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ के मूल म 13 राज्या की माति ही स्विस कटन थपती सत्रमुख शक्ति को इस प्रकार संशोधित करने की तयार हो गय थे जिससे परि-सब को क द्रीय सरकार को राष्ट्रीय चहेंच्या की पूर्ति क लिए पर्याप्त सत्ता प्राप्त हो पत्र मा मानाप प्रभाग मा अनुस्त्र अवस्त्रा १९ तथा मा अस्त्र मा समित्र सरकार के निमाण के लिए स्विटलरलैंग्ड के निमासियों की माया, धम एव राष्ट्रीयताओं सम्ब धी विभिन्नताएँ उपयुक्त अवसर प्रवान करती थी। 2/3 खिस प्रमाण के और होष जनता फेन और इटालियन (रीमन) मापा-भाषी है। स्विस विधानमण्डल म सदस्यों को इन वीना म स किसी भी मापा के बोलने को स्वत त्रता प्राप्त है। सभी वे टनो म लोकत त्रीय व्यवस्था है। स्थानीय हासन के प्रति स्विस जनता म विद्येप रुचि है। स्ट्राम का मत है कि "देश प्रेम न परिसद्य के स्वास्थ्य एव शक्ति को असुन्न रखा है। स्वानीय स्वशासन के असाव मे तथ कायम ही न रहता। स्विट्जरसव्ह की आधुनिक सभीय व्यवस्था के टना की आदत एवं अनुमन पर आधारित है, न कि संबधानिक सिंबा तो एवं विदेशी उदाहरणा

ित्तस संघीय व्यवस्था का अमेरिकी एव आस्ट्रेलियाई संघीय व्यवस्था से अधिक साम्य है और कनाडा के संघीय स्वरूप से वर्षसाठत कम साम्य है। अमेरिकी एव ई के लिस संघिया के संघीय का कारण, स्ट्राण के अनुसार, 1848 ई एव 1874 व्यवस्था की संघीयनकर्तावा के डारा अपन देश की संस्थाओं को जान-अपनी विद्ययताएँ है। ज्याहरण के लिए, स्विस संविधान में स्विस राष्ट्र की जिस व्य

में चर्चा की गयी है वह अमेरिकी सिवधान को अनात है। पर तु स्विस सिवधान में सिक्तियों का विभाजन इस प्रकार किया गया है कि अविहास्ट शक्तियों ने टना को प्रवान की गयी है। के टन अपने-अपने क्षेत्र में स्वायत्त सता-सम्पत्र है। उनके अपने पृथक सिवधान हैं, जि ह वे सशोधित कर सकत हैं। वेकिन के टनो पर तीन प्रतिव प हैं (1) प्रत्येक के टन का सिवधान गणतन्त्रीय होना चाहिए। (2) के टना के सिवधान को कोई अवस्था सधीय सिवधान के विकद्ध नहीं होनी चाहिए। (3) के टना के सिवधान में जनमत सब्रह या जन सहमति द्वारा ही सबीधन या पुनस्रशोधन (vevi sion) किय जाने की अवस्था है। स्विटजरलण्ड म राष्ट्रीय नागरिकता से सम्बिधत कोई विधि नहीं है, अपितु के टनो की अपनी अलग-अलग नागरिकताएँ हैं। जो के टन का नागरिक होता है वही स्विह्म नागरिक होता है हो स्वित्त नागरिक भी होता है।

सभीय व्यवस्थापिका का उच्च सदन राज्य-परिषद (Council of States) के टनो का प्रतिनिधित्व करता है और प्रत्येक के टन को दो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त है। इन प्रतिनिधियों को चुनने एवं उनकी सेवा सम्बन्धी धार्तों को निर्धारित करने में प्रत्येक केटन स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त स्विस सधीय सविधान में विना के टनो की सहमति के कोई भी सदीधन सम्मव नहीं है।

स्विस सधीय व्यवस्था की एक अय विद्यापता यह है कि स्विस सधीय याया स्था को सविधान की व्याख्या का अधिकार सयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च याया स्था की माति प्राप्त नहीं है। स्विद्जरत्मण्ड म सविधान की व्याख्या का अधिकार सधीय व्यवस्थापका को प्राप्त है। स्विस सधीय यायास्य (Federal Tribunal) को के टना के मध्य विवादा का निणय करने का मोसिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है और सभी प्रकार के पुनरावेदनीय सामलों के लिए वह देश का सर्वोच्च यायास्य है।

समीक्षा— स्वित सधीय सरकार को बेदेसिक मामला, राजदूतो को विदेशा में निमुक्त करने एव विदेशी राजदूती का स्वागत करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त युद्ध एव शार्ति, विदेशो से सिंधमी, सिनिक व्यवस्था, आतिरिक शारित एव व्यवस्था, व्यागियम, व्यवसाय, बैंकिंग, डाक तार, रेल, उच्च शिक्षा आदि विद्या पर सधीय सर कार को प्रण नियनण प्राप्त है। उत्योग एव बीमा राजकार्यों का निर्माण एव उनकी रक्षा, समाचार-पन्नो पर नियनण एव जिक्षा प्रसार समवर्ती विषय है। परंतु सधीय सासन की शक्तियों में निरत्तर वृद्ध हुई है। जुक्च (Zurcher) के अनुसार सथ शासन की बिद्ध से लहा उसकी प्रतिकाश से बिद्ध हुई है। वहां केटना की शक्ति का शक्ति हुस हुता है। आहे (Andre) ने तो यह सदेह व्यक्त किया है कि यदि के प्रीय सिक्त इसी प्रकार केटनो की सत्ता का अतिक्रमण करती रही तो नेटन सधीय आदर्श का पालन करने वाले विशुद्ध जिला प्रशासन वन जायेंगे। युद्ध, आधिक मदी, सामा जिक सेवाओं की बढती हुई आवश्यकता एव अनिवायता तथा यातायात व उद्योग के अप में प्रतिकाश के विश्व से हुई है। स्वित परिस्व इसका अपवाद नहीं है। साम रासन नी शक्तियों में विद्ध हुई है। स्वित परिस्व इसका अपवाद नहीं है।

पर तु सभीय द्वाक्ति की बद्धि के पश्चात भी स्विस के टना को पर्याप्त अधिकार एव स्वायत्तता प्राप्त है। उदाहरण के लिए, के टना के "पायालया द्वारा सधीय विभिया लागू की जाती है। के टना के कमचारियों के द्वारा ही सधीय शासन के शायित्व निमाय जाते हैं। के टना के कारा सेनाओं का भी प्रव ध किया जाता है। स्विस सधीय सरकार द्वारा तो केवल उनका निरीक्षण एव निर्देशन ही किया जाता है। स्विस सधीय सरकार को शक्तिया भे जब भी बद्धि को गयी है तब वह विना विरोध या अवरोध के नहीं हुई है। प्रत्येक विधेयक को विधि वनने के पूब जनता द्वारा जनमत-सम्रह के माध्यम स स्वीकृत होना चाहिए। सपीय सवोधन के लिए तो यह व्यवस्था अनिवाय है। स्विस सघीय सविधान में सधीवन के लिए जनता के समयन के जीति रिक्त आधे स अविक के टनो की सहम्रति भी आवश्यक होती है। स्विस जनता सहज ही ऐसे किसी विधेयक को स्वीकृति नहीं देती है। अत सध की शक्ति म असाधारण बद्धि कभी नहीं हुई अपितु परिस्थितिया की आवश्यकता के अनुसार ही शक्ति में बद्धि हुई है।

स्विस एव अमेरिकी संबीय व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन निम्नवत है

(1) स्विस संधीय शासन को अमेरिकी संधीय शासन की अपेक्षा अधिक एव व्यापक शक्तिया प्राप्त है। सविधान के अनुसार संधीय शासन द्वारा के टनो को उनके क्षेत्र, निष्टिचत सीमाओं के आतगत सप्रभुता के प्रयोग एवं अधिकारों तथा स्वतं तता की प्रतिभृति प्रदान की गयी है।

(2) स्विस सपीय शांसन एव के टनी के अधिकार क्षेत्र सपुक्त राज्य अमेरिका के सपीय शांसन एव राज्यों के शांसना व जनके अधिकार क्षेत्र की माति स्वष्ट नहीं है। स्विस सपीय व्यवस्था के जात्मत अनंक सपीय विधियों—सिन विधियों सिहत —के निया वयन के लिए सधीय शांसन को के टनो के अधिकारिया पर निमर रहना पढता है। कुछ विभागों के सन्वस्था में स्विस सपीय शांसन पूणक्षेण आत्मनिमर है। स्मरणीय है कि सपुक्त राज्य अमेरिका में सवीय शांसन एव राज्या के शांसन के अवग-अतम जीविंगरी होते है।

(3) सयुक्त राज्य अमरिका की माति स्विटनरलण्ड के सपीय "यायालय को किसी भी सपीय विधि को अवधानिक घोषित करने का अधिकार नहीं है। अत स्विस सधीय यायालय को अमेरिकी सर्वोच्च "यायालय के समान "यायिक पुनरीक्षण का अधिकार नहीं है।

स्ट्राग ने निम्न अब्दो मे स्विस ब्यवस्या का सार स्पष्ट किया है "स्विस परिसाप म अविश्वट शक्तिया के टेनो को प्राप्त है, सविधान सर्वोच्च है विकन जनमत-सग्रह एवं उपन्का (imitative) के माध्यम से हर विषय पर पूण लोकप्रिय नियंत्रण को व्यवस्था है। अंत में स्विस संपीय न्यायपालिका को सविधान की व्याख्या का अधिकार प्राप्त नहीं है।"

सोवियत रस एव सघवाद

सावियत स्त के स्टालिन सविधान (1936 ई) क द्वारा सधीय व्यवस्था की स्थारना भी गयी है। स्ट्राग के न्यानानुसार सधीय व्यवस्था के सावियत स्त क नवीन एव अपसार्त भी सिव नमून का प्राचीन सथा ने साय तुलनात्मन अध्यवन सामप्रद है। स्त म सधीय व्यवस्था का विकास विल्कुल मिन परिषदा म हुआ है। स्तरणीय ह कि 1918 ई का निनन ने मीलिन सावियत सविधान का सम्ब मूरापीय स्त से ही था का स्ती सावियत सधीय समाजवादी मणराज्य (R SFSR) के नाम सं जात है। 1923 ई म सावियत समाजवादी मणराज्य स्थ को स्थापना हुई थी। यूरोपीय रूस (RSFSR) के साथ तीन अप प्रदेशा (जिनम यूनेन (Ukraine) मी सामिल था) न स्विच्छत मिलन स सावियत समाजवादी सप गणराज्य स्थापित हीते गये, इसी सथ म रामिल होते जले नय। 1936 ई में 1923 ई के सविधान के स्थान पर नवीन सविधान, जिले स्टालिन सविधान की सक्षा न 1936 ई का सविधान की सारा 13 के अधीन 1936 ई का सविधान सविधान की भारा 13 के अधीन 1936 ई का सविधान सविधान सविधान की भारा 13 के अधीन 1936 ई का सविधान सविधान की सारा 13 के अधीन 1936 ई का सविधान सविधान की सारा 13 के अधीन 1936 ई का सविधान सविधान की सारा 13 के अधीन 1936 ई का सविधान सविधान की सारा 13 के अधीन 1936 ई का सविधान सविधान सविधान की सारा 13 के अधीन 1936 ई का सविधान सविधान की सारा सविधान का स्वान निम्न हैं। सविधान का सविधान का सविधान मिलन सविधान की सारा 13 के अधीन 1936 ई का सविधान सविधान की सारा सविधान की सविधान मिलन सविधान मिलन सविधान सविधान की सविधान की सविधान मिलन सविधान सविधान की सविधान का सविधान का सविधान का सविधान मिलन सविधान की सविधान का सविधान का सविधान मिलन सविधान की सविधान सविधान की सविधान का सविधान मिलन सविधान की सविधान का सविधान मिलन सविधान की सविधान सविधान का सविधान मिलन सविधान का सविधान का सविधान सविधान सविधान का सविधान सविधान का सविधान सविधान का सविधान सविधान का सविधान सविधान सविधान सविधान सविधान सविधान का सविधान सविधान सविधान सविधान सविधान सविधान का सविधान सविधान का सविधान सव

रूती सथ, यूनेन, बाइलो रूस, उजबेकिस्तान, कलखिस्तान, जाजिया, अजर थेजान, लियुआनिया, लटविया, किरणजिस्तान, तुकमानिस्तान, एस्टोनिया, मोस्या-विया और आरमीनिया।

सोवियत सघ में समुक्त राज्य अमरिका, कताबा, स्विट्जरलण्ड णव आस्ट्रे विया की माति द्विस्तरीय—केन्द्र व राज्य या प्रान्त या केन्द्रना—संपीय व्यवस्था नहीं है। गोवियत सप में 4 प्रकार की घटक इलाइया है, जो क्रमश्च सप गणराज्य (Autonomous Republics), स्वायसखासी गणराज्य (Autonomous Republics), स्वायसखासी गणराज्य (Autonomous Republics) है। उत्तरासी प्रवेश (Autonomous Republics) है। स्सी सप म 15, जॉजिया में 3 और अजरवजान और उजवेकिस्तान म प्रयेक म एक-एक स्वायसखासी गणराज्य है। इसके अतिरिक्त, 9 स्वायसखासी प्रवेश (Autonomous Reguns) एव 10 राष्ट्रीय कीन (National Areas) है। इसके स्वापत एव मापा के आधार पर की गयी है। सप की इन पारी घटक इलाइयो का सुन्नीम सोवियत के उज्ज यस्व---राष्ट्रीयता सावियत (Soviet of Nationalities)—म प्रतिनिधित्व प्राप्त है। प्रवक्त गणरा य को 25, स्वायतसासी

⁴⁹ The Union of Soviet Socialist Republics is a federal state formed on the basis of a voluntary union of equal Soviet Socialist Republics—Article 13 of the Soviet Constitution

गणराज्य को 11, स्वायत्तवासी प्रदेश का 5 एव राष्ट्रीय क्षेत्र को 1 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है।

सोवियत रूस का सघ मानने के सम्बाद मा विद्वाना में मतभेद है। सघवाद के प्रसिद्ध विद्वान प्रो ह्वीपरे का कथन है कि रूस का 1936 ई का सविधान अधिक स जिथक जद्ध संघीय (quasi federal) है । व इसके विपरीत, त्रो स्ट्राग ने इसे कम बढ़ सद्य राज्य माना है। " प्रो हैजाड ने सोवियत सद्य को गणतानों के सप की सजा दी है। इस मत-विभाग के लिए सावियत सच की अनेक विशेषताएँ उत्तर-दायी हैं। लिखित एवं कठोर सविधान, शक्तिया का विमाजन एवं सर्वोच्च "यायालय क रूप में स्वतात त्यायपालिका सघीय राज्य की तीन प्रधान विशेषताएँ है। सीवियत क्स की सबीय व्यवस्था अपरी तौर पर इनमें से केवल दो विशेषताओं को पूरा करती है। प्रथम, सोवियत सविधान लिखित है। वह कठोर भी है। उसम सरुगेधन की विशेष प्रक्रिया है। सर्वाच्च सोवियत के दोनो सदनों के 2/3 बहुमत की स्वीकृति सिंव धान मे सशीधन के लिए अनिवाय है । द्वितीय, केंद्र व घटक इकाइयों के मध्य सीवि-यत सघ मे शक्तियो वा स्पष्ट विमाजन भी है। जनुच्छेद 14 के जातगत सघ शासन की शक्तियों का उल्लेख किया गया है और अवशिष्ट शक्तिया घटक राज्यों को प्रदान की गयी है। लेकिन तीसरी अनिवास विशेषता अर्थात निष्पक्ष सायपालिका सोवियत सद्य म नहीं पायी जाती है। अमेरिकी या भारतीय सर्वोच्च यायालय की भाति सवि-धान की ब्याख्या और के द्र व राज्यों के मध्य सम्बाधों के निषय करने का अधिकार सर्वोच्च यामालय को प्राप्त नहीं है अपित प्रेसीडियम को प्राप्त है जो वेन्द्रीय विधान-मण्डल की एक समिति है। यह कायपालक कतव्यो को भी सम्पादित करती है। उपयक्त दो सधीय विशेषताओं की पृति भी आशिक रूप मही हाती है। सोवियत संघ म कुछ ऐसी महत्वपूण व्यवस्था है जो अधिकाश संघीय देशा में नहीं पायी जाती है। वे निम्नलिखित है

(1) घटक गणराज्यों को सोवियत सघ से पृथक हाने का अधिकार प्राप्त है। (अमुच्छेद 17)

(2) 1944 ई में सिविधान में सबोधन करके यह व्यवस्था की गयी है कि पटक गणराज्यों को पृथक रूप स मुरक्षा एव विदेश विनाग गठित करने तथा प्रत्येक पटक गणराज्य को विदेशी राज्या के साथ सम्बंध स्थापित करने व सिध्या करने का अधिकार होगा। (अनुरुद्धेव 18) वेलोरसा तथा यूनन क सोवियत सच गणराज्या को सयुक्त राष्ट्र सच का इसी आधार पर सदस्य वनाया गया है।

⁵⁰ The Constitution of 1936 is at best quasi federal '-Wheare

^{51 &#}x27;The U S S R is nonetheless a federal state'-Strong, C F op cit, p 128

⁵² The U S S R III a federation consisting of a number of constituent Republics —Prof Hazard

(3) सघ गणराज्यों को उपयुक्त दो व्यवस्थाएँ विशेष स्वायत्तता की स्थित प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, अत्येक सघ गणराज्य का अपना सविधान है और उन्ह अपने अधिकार क्षेत्र म[्]आने वाले विषया मं राज्य शक्ति के प्रयोग की पूण स्व तत्रता है (अनुच्छेद 16) संघोष गणराज्या की सीमाओं में विना उनकी सहमित के कोई नी परिवतन नहीं किया जा सकता है (अनुच्छेद 18)।

विश्वनसको ने सोवियत सघ की घटक इकाइया की स्थित पर मत व्यक्त करते हुए कहा है कि 'प्रत्येक सघीय स्थापाच्य की सप्रमुता की अभिव्यक्ति निम्न तथ्या द्वारा होती है—(1) प्रत्येक सघ स्थाराज्य का स्वनिर्मित अपना सविधान होता है, (2) उनका अपना निश्चित क्षेत्र होता है जिसमें उसकी सहस्रति के विना परिवतन

नहीं किया जा सकता, एव (3) उसे सच से पृथक होने का अधिकार प्राप्त होता है।"
सीवियत सच की उपर्युक्त व्यवस्थाओं के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि
सीवियत सम में पटक राज्यों को अपेक्षाकृत अधिक स्वायत्तता प्राप्त है और अप
समा को अपेक्षा वह अधिक श्रेट्ठ है। पर तु विचारकों के अनुसार तथ्य इसके विपरीत
है। सीवियत सिबधान में अनेक ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो उपर्युक्त व्यवस्थाओं को सीमित
करके पटक इकाइया की स्वायत्तता को समाप्त कर देती हैं। सीवियत सच की इन
एकात्मक प्रवत्तियों के कारण ही हरमन फाइनर ने उसे एकात्मक राज्य माना है।

सोवियत सघ म एकात्मक प्रवृत्तिया निम्नवत् हुँ

सावयत तथ म एकारलक अवृत्तया तब्नव्यत् ह (1) सयुक्त राज्य जमेरिका एव मारतीय सच की माति सोवियत सविधान के सशोधन म पटक इकाइयो की स्वीकृति आवस्यक नही है। सवॉच्च सोवियत की सविधान में सशोधन का एकाधिकार प्राप्त है। एकदलीय व्यवस्था के कारण दोनो सवनो में 2/3 वहमत प्राप्त करना कोई कठिन काय नहीं है।

(2) सघ एवं घटक इकाइयों के मध्य शक्ति विमाजन में भी पर्याप्त असमा-नता है। शक्ति विमाजन का आधार शणना एवं अवसीय (Enumeration and Residium) का सिद्धान्त है। सच सरकार को अत्यिषक व्यापक शक्तिया प्रवान की गयी है। ³⁴ इकाइया को प्रदत्त शक्तियों सच की भाति महत्वपूण नहीं है। शक्ति विमा

⁵³ The U E S R declares it a federal union but in reality it is a highly unitary state '-Finer, H The Governments of Europe p 634

Europe p 634

54 अनुच्देद 14

सपीय सरकार को प्रदत्त मुख्य शक्तियाँ निम्न हैं वैदेशिक सम्बाध, सिध्या की
स्वीकृति एव अस्वीकृति, युद्ध एव शान्ति के प्रस्त, साथ म नवीन गणराज्यों की
प्रवेश, सीवियत सथ के सविधान के पालन सम्बाधी प्रस्त, साध्य गणराज्या की
सीमात्रा की स्वीकृति एव उसम परिवत्तन, राज्य एकाधिकार के अधीन विदेशी
व्यापार, राज्य की मुरक्षा, राज्यीय आधिक योजना का निर्धारण, यातायात एव
सचार व्यवस्था मुद्रा एव साक्ष, राज्य बीमा समठन, शिक्षा एव स्वास्थ्य, प्रम्
विधान, याधिक व्यवस्था दीवानी एव भीजदारी सहितार, सथ की नागरिकता, शमादान, बक, औथींगिक एव कृषि-सस्थाना का प्रशासन वादि।

जन में परिवर्तन या संशोधन के लिए इकाइयों की स्वीकृति की आवश्यकता

नहीं है।

(3) सोवियत सपीय मिन्नमण्डल मंदी त्रकार के मनालय होते हैं अखिल सपीय मनालय (All union ministries) एवं सप-गणराज्य मनालय (Union-Republic ministries) । अखिल सपीय मनालयों का क्षेत्र सम्मूण सोवियत सप हैं। सपीय गणराज्य मनालया के द्वारा के द्वीय शासन सप गणराज्यों के समान मनालयों के कार्यों का निरीक्षण करता है। स्पष्ट है कि केन्न का सपीय इकाइया पर पूण नियन्नण हैं।

(4) अनुच्छेद 14 के अधीन सधीय श्रासन को सप गणराज्यो एव विदेशी शक्तियों के सम्बन्ध को नियाजित करने के अधिकार है। इसके अतिरिक्त, सब गणराज्या के सैनिक सगठन के नियजण एव निवंदान से सम्बन्धित सिद्धातों को निर्धारित करने का सभीय शासन को अधिकार है। सत्य तो यह है कि के ब्रीय सरकार का सप-गणराज्यों पर इतन कठोर नियजण है कि सब धुयक होने अथवा विदेशों से पृयक सम्बन्ध स्थापित करने की वे कस्पना ही नहीं कर सकते। के ब्रीय निदंशन के विपरीत किया गया जनका प्रत्येक कार्य किया गया जनका प्रत्येक कार्य कार्यित करने की विषयी करम माना जाता है।

(5) अनुच्छेद 20 के अधीन किसी भी सधीय गणराज्य का कोई कानून यदि सधीय विधि के विरुद्ध होता है तो ऐसी स्थिति में सधीय विधि ही माय होती है।

(6) सोवियत सघ के मिनमण्डल को सघ गणराज्य के मनिनमण्डल के निणयों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है। सोवियत के द्वीय शासन के हायों में यह एक ऐसा विशेषाधिकार है जो सघीय सिद्धात एवं व्यवहार के ठोक विपरीत है।

(7) सीवियत रूस में प्रीक्षूरेटर जनरल (Procurator General) नामक एक के द्रीय अधिकारी होता है। यह सम्पूण देश में सीवियत के द्रीय विधि के क्रिया- वयन के लिए उत्तरदायी है। प्रोक्षूरेटर जनरल को इस सम्बन्ध में इतनी ब्यापक शिक्त्य प्राप्त है कि वह सभी मनावायों एवं प्रशासकीय अधिकरणों पर नियं रण रखता है। उसकी शक्तिया इतनी ब्यापक एवं पूण है कि ऐसे किसी अधिकारी का कीई अप उदाहरण किसी अप सधीय शासन में उपलब्ध नहीं है।

(8) सपीय शासन का सम्पूण देश की आधिक व्यवस्था पर पूण नियानण है। वदेशिक व्यापार, यातायात, सचार, बैको की व्यवस्था, कृषि, उद्योग घासे, मुद्रा-व्यवस्था, राज्य-वीमा आदि विषयो पर के द्वीय धासन का नियानण है। सक्षेप म के द्र शासन द्वारा ही सम्पूण राष्ट्रीय व्यव्यवस्था के सचायन की योजना बनायी जाती है। सम्पूण वेश का एक ही राष्ट्रीय वजट होता है। इसी म सघ-गणराज्यो के वजट मी सम्मितित होते हैं। सारे देश के लिए एक ही नियोजन व्यवस्था होती है। राष्ट्रीय नार्यिक नियोजन को एकीकृत व्यवस्था के कारण के द्रीय शासन का सारे देश पर पूण नियानण होता है।

- (9) प्रेसीडियम का भी सघ गणराज्या का नियात्रत करन की शक्ति प्राप्त है। प्रेसीडियम उनने निणया को रह कर सकती है।
- (10) एकदलीय व्यवस्था व कारण इस व दीकरण की प्रवित्त को और अधिक दल मिला है। रूस म एरमात्र दल साम्यवादी दल है। उमका अनुशासन फौलादी है। सम्पूर्ण जन जीवन पर उसका एरछन राज्य है। प्रशासन सम्बंधी समी नीतिया का निर्माण इसी दल के चाटी क नताजा द्वारा किया जाता है। स्पष्ट है सप गणराज्यों के प्रशासन पर भी साम्यवादी दल वा नियायण होता है।

सोवियत सच की वस्तु स्थिति

सोवियत रूस पश्चिमी संघा से पृथव और मिन है। सावियत नेताओं के अनुसार वह सच्चा सप है। सोवियत सप राष्ट्रीयता पर आधारित है। घटक इकाइया को पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त है। सथ की इकाइया की सथ स पृथक होने और पृयक वैदेशिक सम्बाध एव सनिक संगठन बनाने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे अधिकार अय सघा म घटक इकाइया को प्राप्त नहीं हैं। सोवियत नेताओं के अनुसार सोवियत सधीय सविधान के दो प्रमुख लक्षण हैं—(1) सघ म सम्मिलित इकाइया राजनीतिक रूप से स्वतान है और सम म शामिल हाने के पश्चात आंशिक रूप मे वे स्वायत्तरासी हैं। (2) सविधान म एसी व्यवस्या है कि इस स्वायत्तता की रक्षा हो सके। घटक इनाइया की स्वायत्तता एव उसकी रक्षा के लिए उचित प्रावधान सोवियत सविधान म है अत सोवियत सथ का सविधान सच्दा सधीय सविधान है। उपयुक्त विश्लेपण स ऐसा आभास होता है कि सोवियत सघ अय सघी से श्रेष्ठ है। परतु वस्तु स्थिति इससे भिन है। सोवियत सविधान की एक धारा द्वारा जहा स्वायत्तता की व्यवस्था की जाती है वहा उससे सलग्न दूसरी धारा उसका खण्डन करती है। उदाहरण के लिए, सधीय राज्या की अपने प्रथक सनिक सगठन बनाने का अधिकार है। परंतु अनुच्छेद 14 के अनुसार केद्रीय शासन की सनिक सगठन सम्बाधी सिद्धाता की निश्चित करने का अधिकार प्राप्त है। यही वदेशिक मामलो के सम्बाध में सत्य है। एक तरफ सघ गणराज्यों को स्वतान वदशिक सम्बाध स्थापित करने का अधिकार है तो दूसरी तरफ अनुच्छन 14 (व) क द्वारा के द्रीय शासन को इस स दभ म नियम निर्वारित करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

गणराज्यों को सघ से पृथक होने की स्वत जता है। सिद्धात में यह ठीक है परत व्यवहार म पृथक होने या अलगाव की चर्चा की ऋति विरोधी चर्चा है जिसकी किसी सघ गणराज्य को कभी भी अनुमति नही दी जा सकती। सघ से पृथक होने के विचार को साम्राज्यवादी शक्तिया का पडयान कहा जाता है और उसे साम्यवादी दल के नेता किसी स्थिति में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अत सोवियत सथ में कंद्रीकरण की गम्भीर प्रवृत्ति है। विशि सकी 55 द्वारा

⁵⁵ Vyshinsky The Law of the Soviet State, 1948, pp 286 87

सघ गणराज्यों की स्थिति पर व्यक्त बिचारों से यह स्पष्ट है कि वे केंद्र के अनुशासन व निर्देशन म काय करते है।

सोवियत रूस के सघ म के द्रीकरण की प्रवृत्ति को रूसी नेता छिपाने का प्रयत्न नहीं करते, वरन वे उसे पूजीवादी देशों के के द्रीकरण से श्रेष्ठ मानत है। पूजी- बादी सपीय देशों म के द्रीकरण तो कमचारियों का के द्रीकरण है। विशिक्ति के अनुसार "सोवियत सघ का निर्माण लोकजा तिक के द्रीकरण से सिद्धां ता पर हुआ है जा पूजीवादी राज्या के कमचारीत तात्मक के द्रीकरण से पूजत भित्र है।" उसने 'आयारभूत प्रता, सामाय मानदशन तथा एक ही योजना के अनुसार पूरे राज्य के आर्यिक विकास की अधिकतम एक रूपती के हैं।

सत्य तो यह है कि "सोवियत सच सास्कृतिक हिष्ट से सच होत हुए भी आर्थिक एव राजनीतिक हिष्ट से एकात्मक राज्य है।' जारकाखीन रूस म प्रान्ता की जनता एव अप सास्कृतिक अख्यसंस्पको पर घोर अख्याचार किये जाते थे और इन अख्य-संस्पको ने शासन के इस दमन का प्रवल विरोध किया था। जारकालीन शासन ने विमिन्न मागई एव सास्कृतिक हकाइयो की भाषा एव सस्कृतियो को दवाने एव जन पर रूसी मागा एव सस्कृति को लादने का मरसक प्रयन्त विया था। ता एव सास्कृतिक अख्यसंस्थकों के इन विद्रोहों में हजारो लोगो को मौत के घाट जतार दिया गया था। लेकिन सोवियत रूस में विमिन्न मागाई एव सास्कृतिक राष्ट्र-जातिया को आज अपनी मागा एव सस्कृति की पृण सुविधा एव स्वतंन्ता प्रान्त है।

जर्मनी मे सघवाव

जमनी मे सपवाद का इतिहास बहुत पुराना है। अ विस्माक के नेतस्व में 1871 ई मे जमनी का एकीकरण हुआ और राष्ट्रीय राज्य का उदय हुआ । इससे पूव जमनी म सधीय प्रवित्ता हिष्टगोचर होने लगी थी। जमन राज्यों के सब के निर्माण में विदेशी आक्रमण प्राथमिक कारण सिद्ध हुआ था। उसकी चरम परिणित 1871 ई एवं 1919 ई म हुई थी। अ 874 ई मे चाल्स महान की मृत्यु के परचात उसका विशाल सामाज्य टुकडे टुकडे हो गया था। समूण मध्यपुण म साम तवाद का बोलबाला बना रहा। पिवंत्र रोमन साम्राज्य तो साम तबाद की विकेट्रित व्यवस्था की आवृत करने वाला एक आवरण मात्र था। इसके अधीन दो प्रतिस्पर्धी राज्या— आस्ट्रिया एव प्रशा—का उदय हुआ। नेपोलियन के पूव इस प्रदेश मे आस्ट्रिया एव प्रशा के अतिरिक्त 1800 स्वतन्त राजनीतिक की व थे। उसस्य कमन क्षेत्र राष्ट्रीय मावना के विकास के लिए उपयुक्त भूमि नहीं थी। प्रत्येक प्रदेश की अपनी सीमा एव आधिक तानेव दी थी। प्रत्येक क्षेत्र के अलग-अलग सिक्के थे। उनकी अपनी सीमा एव राजनीतिक व्यवस्थाएँ थी। फास की राज्यनाति एव नेपोलियन के आक्रमण ने जमनी

⁵⁶ Strong, C F op cal, p 123 57 Finer, H op cal, p 171

मे राष्ट्रीयता की मावना को ज म दिया। 1800 स्वत न राजनीतिक क्षेत्रों के स्थान पर 33 राज्यो का निर्माण किया गया और पवित्र रोमन साम्राज्य का अत कर दिया गया। 1815 ई मे जनन परिसघ (German Confederation) का निर्माण हुआ था जो आस्ट्रिया एव प्रशा के मध्य अतिम सघप के लिए, स्ट्राग के शब्दों में, प्रस्तावना या आरम्म था। 58 1815 ई से 1842 ई तक परिसघ के काल म, फाइनर के अनुसार, प्रशा के अधीन जमन सघ के निर्माण की भावना बलवती होने लगी थी । परिसय मे राजनीतिक दला एव राप्ट्रीय मावना का विकास होने लगा था। फलत परिसघ की इकाइया संघीय सविधान के निर्माण एवं आर्थिक एकता की दिशा में अग्रसर हुई थी। 1848 ई की क्रांति हुई और जास्ट्रिया तथा प्रशा में सघप प्रारम्भ हुआ । इसमे आस्ट्रिया विजयी हुआ । इसी काल मे आर्थिक क्षेत्र म चुनी सघ का निर्माण हुआ। इससे एकता स्थापित हुई। 1848 ई तक सघ के निर्माण मे आर्थिक प्रयोजन प्रधान थे। पर तु इसके पश्चात राजनीतिक तत्वा न प्रमुख स्थान ले लिया। 59 1848 ई म फासीसी कात्ति के पश्चात संघीय योजनाओं पर गम्भीरता पूर्वक विचार होने लगा था। आस्ट्रिया ने सब मे शामिल होने से इकार कर विया। ववेरिया ने अनिच्छापूबक कार्ति की सफलता के पवचात ही अपनी सहमति वी थी। 550 सदस्या वाली एक सविधान सभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ। प्रशा के इसम 141 सदस्य थे। आस्ट्रिया मे काति हो रही थी अत वह केवल दो सदस्य ही भेज सका। अत सविधान समा की सकलता प्रधा के सहयोग पर निमर करती थी। प्रशाने अवसर का लाम उठाते हुए सविधान समाका अधि वेदान उस समय आहूत किया जब आस्ट्रिया म नाति सफल हो चुकी थी, परतु क्रांति के वेग के कम होने पर बहुत स जमन नरेशा ने प्रशा के राजा के नेतृत्व को अस्वीकार कर दिया। प्रशा का शासक भी नान्तिकारिया की वाधाजा के जातिरक कारणा स आस्ट्रिया के साथ सघप के लिए तैयार न था। 'फ्रेंक्फोट की ससद' मौलिक अधिकारी सम्बंधी मतभेदो के कारण असफल हो गयी। लेकिन उसन सघीय सविधान को स्वी कार कर लिया था। इसम आस्ट्रिया को शामिल नहीं किया गया था। द्विसदनीय विधानमण्डल की व्यवस्था की गयी थी और सधीय शासन को व्यापक शक्तियाँ प्रदान मी गयी थी । आस्ट्रिया ने इसे स्वीकार नही किया । दक्षिणी जमन रियासतें आस्ट्रिया के सरक्षक की इच्छुक थी। विस्माक ('आधुनिक जमनी का जनक') ने चतुर खिला^{डी} की भौति प्रशा का जमन एकीकरण की हर्ष्टि स नेतत्व किया। उसन आस्ट्रिया नी यिरोप प्रारम्म कर दिया और फास से मित्रता की तथा सावमीम सताधिकार पर निर्वाचित जमन ससद की स्थापना की माँग की। विस्माक ने सघीय सत्ता का अधिक व्यापक बनाने और आर्थिक एव वदेशिक सम्बाधा तथा जमन सशस्त्र सना का नतृत्व संघीय शासन को सौंपन का प्रस्ताव किया। जमन संसद द्वारा सवसम्मति सं निगय

⁵⁸ Strong C F Ibid , p 123 59 Finer, H op cit , p 174

करते की व्यवस्था को विस्माक ने समाप्त करने का सुकाव दिया। इसे आस्ट्रिया की सरकार मानने को तैयार न थी भयोकि बहुमत द्वारा निणय का अथ प्रशा की सफलता होता। अनएव आस्ट्रिया एव राइन नदी के निजले क्षेत्र के राज्यो को पृषक रखते हुए एक नदीन योजना वनायी गयी। इसे भी कास्ट्रिया ने अस्वीकार कर दिया। इस पर प्रशा ने परिसाध की समाप्ति और निलम्बित होने की घोषणा कर दी। 1866 ई में आस्ट्रिया एव प्रशा म युद्ध प्रारम्भ हो गया जियमे ऑस्ट्रिया पराजित हुआ और जमन सख के निर्माण की सबसे वही बांचा हूर हो गयी। आस्ट्रिया पराजित हुआ और जमन सख के निर्माण की सबसे वही बांचा हूर हो गयी। आस्ट्रिया को सब से पृथक कर दिया गया। लेकिन अभी अनेक बांचाएँ वाकी थी पर तु के द्वीय घुरी अब एक ही थी। युद्ध-काल में उत्तरी राज्यों ने अपने को काफी असुरक्षित अनुमव किया था। किकिन प्रशा के साथ युद्धकालीन सम्पक और सधि वो के फलस्वस्थ जरारी लगन परि-स्था (North German Contederation, 1867) का जम हुआ। यही 1871 ई के जमन साम्राज्य का मसूना बना। इसकी पुख्य विश्वेदताएँ निम्मवत् यी

 एकता की स्थापना के पश्चान राज्यों को बहुत बडी माता में स्वत"त्रता प्रदान की गयी।

(2) नदीन राज्यों के अंतिरिक्त प्रत्येक राज्य को सवीय ससद में पहले जो स्थान प्राप्त थे वे ही दिये गये। प्रदा को 42 म से 17 स्थान प्राप्त थे अत बहुमत के लिए कैवल पाच मतो की आवश्यकता थी।

(3) सबैजानिक सलोधन के लिए 2/3 बहुमत जरूरी था । फ्लत छोटे राज्या को सगठित होकर एकजुट हो जाने पर सशोधन के सन्दम में निपेधाधिकार प्राप्त था। लेकिन प्रशा के सहयोग के बिना कोई सबैधानिक सशोधन पारिस नहीं हो सकता था।

(4) प्रका का राजा उत्तरी जमन परिसध का सर्वोच्च सेनापति था । सेना सम्बन्धी सभी प्रस्तावा पर सर्वोच्च सेनापति की स्वीकृति जावश्यक थी ।

(5) निर्वाचित सदन रीस्टाग में सप्रमुता अधिष्ठित न होकर सधीय समा (Federal Council) में अधिष्ठित थी ।

(6) सचीम चा सलर किसी सधीय निकाय के प्रति उत्तरदायी न होकर सघ क अध्यक्ष प्रशा के राजा के प्रति उत्तरदायी था।

(7) सघीय विधिया राज्यो द्वारा ऋयाचित की जाती थी।

िन्त पाया पाया क्या निकार के साथ किया भी स्वाह जुलाई 1867 ई से लागू हुआ। परन्तु यह सधीय व्यवस्था जभी जपूण वी क्यांक दक्षिणी रियासते अभी जमन सच से पृथक थी। विदेशिया वरदेमवग एव वाहिन की दक्षिणी रियासतों ने उत्तरी परिसम से सम्य स्थापित करने का निश्चय दो किया पर तु प्रसा के प्रति तीव सदह एव अविश्वास भी प्रकट किया। राजवशीय मानना की क कारण भी यह प्रयत्न सफ्ल न हो सका। केवल इन राज्या स एक उर्दे हो सकी। अह सम्यूण जमनी की सरक्षा के विष्य सो तो वन गया था र

राज्य अभी भी अवसर के अनुकूल स्वतन्त्र रीति से निषय करने के अधिकार को अपन पास सुरक्षित रखना चाहते थे। स्वतात्र व्यापार एव चुगी व्यवस्था के फलस्वरूप वाणिज्य का विकास हुआ था। राष्ट्रीय दला के विकास के फलस्वरूप सघ की राक्ति म वृद्धि हुई। राज्यों में जो तीव्र मतभेद थे वह भी कम हुए थ। विस्माक अपीर नहीं था। दक्षिणी राज्यों का जमन सद्य म आकर्षित करने के लिए वह प्रयत्नशील था परतुवह तेजी या जल्दी म नहीं था। दक्षिणी राज्यों ने पृथक सघ के निर्माण का प्रयत्न किया पर तु वे असफल रहे ! विस्माक की यह धारणा थी कि जमन स्प का निर्माण शक्ति या वल-प्रयोग से हो सकता है या किसी सामा य सकट की अवस्था में सभी राज्य सब में शामिल हो सकते हैं। यह सामा य सकट की अवस्था 1871 ई में फा स एव प्रशाके मध्य युद्ध प्रारम्भ होने स उत्पन्न हो गयी। फ्रान्स इस युद्ध म हार गया । दक्षिणी राज्यों की निरातर उत्तरी सच के विरुद्ध भडकाने वाले प्रधान तत्व का अत हो गया। ववेरिया को छोडकर सभी दक्षिणी राज्यो न इस युद्ध म उत्तरी परिसघ का साथ दिया था। सारी जमन सेनाओ का नेतृत्व प्रशा ने किया या। प्रशा के साथ इस युद्ध को सभी जमन राज्या के साथ युद्ध माना गया। इस युद्ध ने विजयी जमनी का एकीकरण सम्भव बना दिया। ववेरिया ने प्रारम्भ म उत्तरी परिसय मं शामिल होने के बदले मं अनेक रियायता की माग की परन्तु अन्त मं उसे सघ म शामिल होना पडा । उस अनेक रियायते दी गयी थी। बार्डिन (Baden), हेस (Hesse) एव वरटेमवग ने बिना किसी विरोध के जमन संघ के सर्विधान की स्वीकार कर लियाथा। इस प्रकार जमन साम्राज्य का जम हुआ और प्रशाकी राजा जमन सम्राट बना ।

जमन साम्राज्ञीय सविधान (1871 ई) एव सधवाद

विस्माक द्वारा स्थापित जमन साम्राज्य पूरी तरह सथीय नही था। स्वरूप मं वह निश्चय ही 25 राज्या का सथ था। प्रत्यक राज्य की अपनी ससद या विधान मण्डल भी था और राज्या के विधानमण्डला को साम्राणीय विषया को छोड़कर प्राप्त मी विधान स्थान के प्राप्त प्राप्त है अधि वासक के अभीन बहेसित सम्बर्ग, विद्या घासक के अभीन बहेसित सम्बर्ग, विद्या घासक के अभीन बहेसित सम्बर्ग, विद्या घासार, सना, नोसना, चुणी, एक्साइज ब्रजूरी, हुण लेना, रल, नहर, डार्न तार सवार्ग, पुद्रा, वक, पटेंट एवं सर्वाधिकार, माथ एवं नाप, दीवानी एवं पोजदारी सिहितारों, उद्योगा को नियमन, यायिक स्थवस्या जैंव सामा या विषय प । व होय विपया पा सविधान भ उत्सव किया गया या लिन राज्या में प्राप्त अपरिकारित विषया पा सविधान भ उत्सव किया गया या लिन राज्या ने प्राप्त अपरिकारित पा चा प्रत्या को प्रता को प्रता को प्रता ना उत्सव कर दिया गया था और गय प्रता का प्रता को प्रता को प्रता को प्रया का प्रता का विशेष प्रमाव या। प्रता का बनानुगत राज्या हो अपन सथ ना अप्यक्ष एवं जमन सम्राय या। वह प्रता का बनानुगत राज्या हो जमन सथ ना अप्यक्ष एवं जमन सम्राय या। वासर नहीं था। जनमी पा स्वा को चीति वान्यानुगत राज्या होत हुए पी नामसम्ब भ राज्य नहीं था। जनमी पा स्वा का विशेष प्रमाव गा। वसर नहीं भा। जनमी साम्राज का वार्य नहीं था।

पालिका अधिकारी या। अमेरिका, स्विटजरलण्ड तथा आस्ट्रेलिया के सभी में उच्च सदना में प्रत्येक घटक को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हैं लेकिन जमन सध के 58 सदस्यी उच्च सदन बुंडरट (Bundesrat) में अकेले प्रशा को ही 17 स्थान प्राप्त में । अपने पड़ीसी राज्यों के मतो पर उसका एकाधिकार था। सेना, नौसेना तथा वित्तीय मामला से सम्बिध्यत सभी विधेयका को प्रशा अत्वीकृत करके अकेले ही निपेशियकार का प्रयोग कर सकता था। उच्च सदन को ही सध तथा राज्यों एव राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादा का निणय करने के अधिकार प्रदान किये गये थे। अमेरिकी सध म यह कतव्य सर्वोच्च यायालय को प्रदान किये गये थे। अमेरिकी सध म यह कतव्य सर्वोच्च यायालय को प्रदान किये गये हैं। इस सदन म प्रशा का स्पट बहुमत था जिसके कारण इन मामलों म निष्यक्ष निणय कठिन था। जमन सध की व्यवस्थापिका द्विसदनीय थे। निन्म सदन रीस्टाग (Reichstag) की शक्ति नाममात्र की यी। सविधान म संशोधन साधारण विधि पारित करने की प्रणाली से दोना सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा ही सम्भव था।

स्ट्रांग की इप्टि म 1871 ई के जमन साम्राज्य का सम्वाद अद्वितीय था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह सम्र के घटका की स्वेच्छा का परिणाम था। कुछ ने तो कुछक वर्षों तक प्रधा के नेतृत्व म गठित जमन कस्टम सम्र की सदस्यता से प्राप्त आर्थिक लामा का उपमोग भी किया था। सस्य तो यह है कि जमन राज्यों म राज्यों। तिक सम्र हो कि जमन राज्यों म राज्यों। तिक सम्र हो कि जमन राज्यों म राज्यों। तिक सम्र हो कि जमन राज्यों से राज्यों। तिक सम्र हो कि जमन राज्यों से राज्यों। एवं उसके दवाव ने उन्हें प्रशा के नेतृत्व को स्थीकार करने के लिए बाध्य कर दिया था। सीमर जमन सिंधान (Weimar Constitution) एवं सम्रवाव

1871 ई के साझाक्षीय सविधान में एकारमक प्रवित्तयां का बाहुत्य या । वीमर सविधान द्वारा इस एकारमक या के बीकरण की प्रवित्त को और अग्रसर किया गया। वीमर सविधान में 18 घटका के लिए पहले सविधान की मालि 'राज्य' शब्द का प्रयोग न करके 'क्षेत्र' शब्द का प्रयोग किया गया । प्रत्येक क्षेत्र के लिए गणत नीय सविधान निश्चित किया गया। स्मरणीय है विश्वयम विश्वय के फलस्वकर प्रधा की खाक्ति समान्त हो गयी थी। यही नहीं समस्त जमन 'राजवहां का भी जात हो चुका था। अत एकारमक राज्य की स्थापना के लिए तीव आ दोलन "कुक किया गया। अत एकारमक राज्य की स्थापना के लिए तीव आ दोलन "कुक किया गया। अत

इस नवीन सप (वीमर सविधान के अत्यात) की केद्रीय सरकार पर्यान्त शक्तिशाली थी। 1871 ई के सविधान म राज्याध्यक्ष के स्थान पर जनता द्वारा निवाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था की गयी थी।

सभीय शासन की शक्तिया का उल्लेख अनुच्छेद 6 म किया गया था । इमर अनुसार बदशिक एव औपनिवेशिक मामला, सुरक्षा सेनाओ के सगठन एव अनुगान 1, तार-डाक एव टेलीफोन के सचार-साधन, मुद्रा, सीमा-कर, आ तरिक व्यापार, राष्ट्रीयता, आयजन, बहिंगमन, प्रत्यापण आदि विषय सधीय विषय थे। अनुच्छेद 7 र अधीन कुछ विषया मे राज्या एव सधीय शासन को समवर्ती क्षेत्राधिनार प्राप्त था। अनुच्छेद 12 के अनुसार यह व्यवस्था थी कि "सधीय शासन अपनी विधायी शिक्त का जहीं प्रयोग नहीं करता वहा राज्य उसका प्रयोग करेंगे।" पर तु अनुच्छेद 6 म उल्लिखित सधीय शासन की विधायी चिक्त्या पर अनुच्छेद 12 लागू नहीं होता था। राज्य द्वारा पारित विधिया की तुलना मे सधीय विधियों अधिक मा य थी और राज्य विधि एव सधीय-विधिय विवाद अथवा असगित होने पर सर्वोच्च यामालय का निणय अतिम होता वा अर्थात सर्वोच्च यायालय को सधीय-विधिया की व्यास्या का अधिकार प्रदान किया गया था।

1871 ई के सविधान की माति डितीय सदन रीवसरंट (Reichstat) की कें उ एवं राज्या सम्बंधी विवादों में निषय का अधिकार नहीं या अपितु इस हेतु सर्वोच्च 'यायाक्ष्य की स्थापना की गयी थी। उस विधान की व्यास्था का अधिकार प्राप्त था। नवीन सविधान के अधीन डितीय सदन नी शक्तियाँ पर्याप्तत कम थी। निम्म सदन रीस्टाग वास्तविच विधायी सदन था। दितीय सदन रीचसरेट में अमेरिका एवं आस्तुनिया की नाति समान सर्या में सदस्या के निर्वाचन की व्यवस्था नहीं की गयी थी।

प्रत्यक राज्य अपने क्षेत्र में स्वायक्त सम्पन्न था। उन्ह अपने सिवधान के निर्माण की स्वत त्रता प्राप्त थी। पर तु यह स्वत त्रता नाममात्र की यी क्यांकि यदि कोई 'की र राष्ट्रीय सिवधान या विधि हारा निर्माण्ति किसी दाधित का सम्पादित करने म असफल रहता था तो राष्ट्रपति को सना की सहायता से उन्ह त्रियांचित कराने वा अधिकार प्राप्त था (अनुच्छेद 48)। क्षेत्रा को ब्यवहार में कोई स्वायक्ता प्राप्त नहीं थी।

वीमर सविधान म जनमत सग्रह का भी प्रावधान था। सामा य विधि मा सवैधानिक सरोधन के सदम में जनता एव शासन को जनमत-सग्रह की माग करने का अधिकार प्रवान किया गया था।

स्ट्राम⁸⁰ के अनुसार 'जमनी ने वीमर सविधान म सपवाद की तीन प्रमुख विरोपताएँ फमन सविधान की सर्वाच्चता, सित्तंथों का विमाजन एवं शितियों को विमाजन एवं शितियों को विमाजन एवं शितियों को विमाजन पर ने कि लिए 'याधान्य विद्यान था। फिर भी जमनी की (इस) सभीय व्यवस्था ने अनोकी विद्यान थी। 'प्रमुख विद्यान था। फिर भी जमनी की (इस) सभीय व्यवस्था ने अनोकी विद्यान थी।' प्रमुख की सम्बन्ध सभीय सत्ता से या, दूसरे म उन विषया का उल्लेख था जिह सभीय सत्ता की की के साय-साथ उपभोग करती थी। और तीसरे प्रकार के विषय उल्लिखित नहीं थे कि तु एस मामला म भी सपीय विश्व राज्य की विषय की अपक्षा मान्य थी। द्वितीय उच्च सत्ता वा सगठन जनस्थल्य प्रशा या वा सा सामक जनस्थल्य प्रशा या वेरिया की तुक्ता म दुश्नी सदस्थार पर किया गया था सित्त फलस्थल्य प्रशा म वेरिया की तुक्ता म दुश्नी सदस्थार प्राच विश्व । तुतीय, राष्ट्रपति अमिक्त की मार्तित प्रत्वस्थ रीति स निवाचित होता था। वह कनाहा एवं आस्ट्रेलिया के मधा की

⁶⁰ Strong, C F op est, p 126

माति मित्रमण्डल के माध्यम सं काय करता था परन्त अमेरिका के विपरीत व्यवस्था पिका के प्रति उत्तरदायी था।

नाजी उत्थान और जमन संघवाद

हिटलर के उत्थान और शक्ति म आने के पश्चात अर्थात वृतीय रीक (Third Reich) के अतगत 'क्षेत्र' (Landers) 'प्रशासनिक इकाई' मात्र वनकर रह गये थे। दी यनीफिकेशन एक्ट (The Unification Act) 1933 ई के द्वारा इन क्षेत्रों का शासन गवनरों को प्रदान कर दिया गया था जो हिटलर के प्रति उत्तरदायी होते थे। गवनरों को हिटलर के द्वारा नियुक्त अथवा पदच्युत किया जाता था। फरवरी 1934 ई के एक आदश के द्वारा राज्या की प्रथक नागरिकता भी समाप्त कर दी गयी थी। एक जादेश के द्वारा 'क्षेत्रा' को जो प्रमत्य सम्ब वी अधिकार प्राप्त थे व भी 'रीक' को इस्तान्तरित कर दिये गये थे । राज्य विधानमण्डलो को विधटित कर दिया गया और स्तिमण्डलो को केटीय मन्त्रिमण्डल के अधीन कर दिया गया था। केटीय शासन के निर्देश पर राज्यों के गवनरा द्वारा विधियों को जारी किया जाता था। गह मात्री राज्यो पर नियानण रखता था। हिटलर के अधीन जमनी एकीकृत एव के इ-कत राज्य मे परिवर्तित हो गया था। प्रशासकीय क्षेत्रो का पन निर्माण भौगोलिक आधार पर किया गया था। रीचसरेट (Reichsrat)-क्षेत्रा के प्रतिनिधि सदन-वितीय सदन-को विघटित कर दिया गया था।

दितीय विश्व प्रदोपरात जमनी में सघवाद

नाजी जमनी के पराजित हान पर विजेता राष्टा ने जमनी म राजनीतिक व्य-वस्था की स्थापना के लिए वीमर सविधान आधार की मानते हुए विचार विमश प्रारम्भ किया था। चारा वडी शक्तिया जमनी म संघीय ध्यवस्था की स्थापना के पक्ष में थी। जमनी की उदारवादी जनता भी सधात्मक शासन की समधक थी। पश्चिमी राष्ट्रो (ग्रेट ब्रिटेन फास एव सयुक्त राज्य अमेरिका) ने एक ढीले ढाले सथ के निमाण का समयन किया था। सोवियत रूस को यह संदेह था कि सशक्त के दीय शासन भविष्य में किसी विस्माक या हिटलर के उत्थान के लिए माग प्रशस्त कर सकता है। 61 जमनी में सरकार की शीघ्र स्थापना के लिए पश्चिमी राप्टों न सोवियत रूस स प्रथक रहकर काय किया और सितम्बर 1948 ई म बोन स्थित जमन सविधान समा के विचाराध जमन राज्या के सघ के सविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। जमन सधीय गणराज्य (परिचमी जमनी) का जाम सितम्बर 1949 ई म हवा । इसके सविधान को जमनी ना आधारभूत नानून (Basic Law) कहते हैं। इसे वान मनिधान (Bonn Constitution) भी कहत है।

पश्चिमी जमनी म 11 सदस्य राज्य (Lander) है जिसम कुल जमन सस्या का तीन चौथाई भाग निवास करता है। 'वोन सविधान द्वारा दा सूचिया—सघीय मूची

⁶¹ Strong, C F op at, p 127

एव समवर्ती मुची—का उल्लेख विया गया ह । सभीय मुची व विषया पर मधाव द्वारक की विधि जिमाण का पूण अधिकार प्राप्त है। यह विषय है वदीतक मामले, वधीय नागिरवता, आवागमन क साधन, पारपप्त, बहिंगमन, प्रत्याप्ण, मुद्रा, मम्मित, मण, एव नाप, सीमा-कर, रस, हृदाद यातायात, डाक एव सचार-व्यवस्था निर्दे दूसर सूची म वेन्द्र एव राज्या का समवर्ती क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इस मुची म विधि, वाना जिक वीमा, आधिक नियमन, राज्य-वदार्थी ना यातायात, समुद्री एव तटीन वहां रानो, श्रमिक कानून, वणानिक साध, संडव एव माटर यातायात आदि विषया वा उल्लेख है। सविधान कं अनुसार जिन विषया पर सथ का विधि निमाण का अधिकार नहीं दिया गया है, उनके सम्बन्ध म राज्या (Landers) का विधि निमाण का अधिकार प्राप्त है । इसक अतिरिक्त, वर्षीय विषया पर को घटका को सरकारों का विधि निमाण कं अधिकार प्राप्त है कि सा प्राप्त है कि सा प्राप्त के अपन को सरकारों का विधि निमाण के अधिकार प्राप्त है। इसक अतिरिक्त, वर्षीय विषया पर को घटका को सरकारों का विधि निमाण के अधिकार प्राप्त है। सकत हैं। स्वर्षा करें।

विदेश सवा, सधीय वित्त, सधीय रसव, सधीय डाक-नार सवाएँ एव जनाय जहाजरानी सम्बंधी विषया पर सधीय प्रशासन का सीधा नियंत्रण है। सीमा-कर, एका धिकारा, एक्साइज करा, यातायात एव सम्पत्ति-करा स होने वासी आय सधीय सरकार के सिनाधिकार म है। सधीय द्वासन का विधि बनाकर आय-कर एव निगम-कर स होने वासी आय म स अपन ब्यय की पूर्ति हुतु धनराषि की मींग करन का अधिकार है। समाय सामन को ब्या की दश की विधिक एवं आधिक एकता है। समवतीं सूची लम्बी है। सभीय सामन को दश की विधिक एवं आधिक एकता के स्वापक सकता के लिए इन पर विधि बनाने की व्यापक सकता निर्मा निकास कर सक।

सधीय शासन एव राज्यो म अधिकार क्षेत्र सम्ब घी विवादा का निणय करने हेतु सविधान द्वारा सधीय सर्वधानिक यायालय (Federal Constitutional Court)

की स्थापना की गयी है। इस सविधान की व्यारमा का भी अधिकार है।

'बोन' सिविधान बहुत कुछ वीमर सिविधान पर आधारित है। परन्तु बीमर सिविधान की अपेक्षा इसम के प्रीकरण कम है। सिवधान में सधीय ने प्रीकरण के विष रीत एक यह व्यवस्था है कि विधिक प्रस्ताव सधीय समा (Federal Council) द्वारा मा य होना चाहिए। स्ट्राग पिरुमी जमन सधीय गणराज्य की विशुद्ध सधीय राज्य मानता है क्यांकि उसम सिवधान की सर्वाच्चता, शक्तियों के विभाजन तथा सधीय एव राज्या के अधिकारिया के विवादों को हल करने के हेतु एक सर्वोच्च यायालय की व्यवस्था है।

पाकिस्तान एव सघवाद

भारत के विशाजन के फलस्वरूप 15 जगस्त, 1947 ई का पाकिस्तान की जन्म दुजा था। नवीन सविधान के वनने तक भारत शासन अधिनियम (1935) की

⁶² Section 73

⁶³ Strong, G F op cut p 128

ही पाकिस्तान के सविधान की मागवा दी गयी थी। पाकिस्तान का नवीन सविधान हा भागत्यात के वावचात का भा वता के भूषा था । भागत्यात के भागत्यात के भागत्यात के स्विधान समा द्वारा स्वीकार किया गया और 23 माघ सघनाद का व्यानहारिक स्वरूप | 199 1956 ई ते लागू हुआ। 7 अनदूबर 1958 ई तक यह सिवधान प्रभावी रहा और इसी दिन वयून छा ने इसे समाप्त घोषित करते हुए सैनिक तामाशाही की स्थापना इसा १५१ जपून था ११ २८ छना छ नामछ करछ हुँ स्वानक छानासाहा का स्थापम की थी। यह सर्विमान आजू भी पूर्यान्त महत्त्व का है क्योंकि यही दिनक प्रशासन का भाग १ वर घानचारा चार्च वा विद्यानी को स्वामाविक रूप सं प्रमावित मी करता रहा है।

पाकिस्तान म संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गयी। पाकिस्तानी संघ म दो त्रात थे— पूर्वी पाकिस्तान्ध एव पहिचमी पाकिस्तान्। केन्न एव राज्या व शक्तियों को विमाजित किया गया था। शक्तियों के विमाजित में संपुक्त राज्य अमेरिका, स्विटजरतण्ड, आस्ट्रेलिया कनाडा एव सारत म प्रचलित शक्तियों के विमाजन के विद्वात को मायता दो गयी थी। कनाडा एव भारत की मीति समीय एव राज्या का शास्त्रवा का उल्लंख ताम द्वापना—चनान, जा तान एवं तमनता—म नामा भवा था । अवसिन्द्र सक्तिया संयुक्त राज्य भनेरिका, स्विटजरलण्ड एवं आस्ट्रेनिया की मानि प्रान्ता की प्रदान की गयी थी।

सधीय सुची क्ष म 30 विषय थे जसे — सुरक्षा, वैदेशिक सम्बर्ध, नागरिकता, त्रधाव प्रचा च उठ १४४४ च चठ चुड़्या, उपायक वाच प्राप्ताराच्या, व्यापक वाच प्रमुख्या के साथ व्यापार एवं वाचिक्य युद्धा, आयिक नियोजन एव राष्ट्रीय आधिक सम वय, सावजितक ऋण एव जहाजरानी, बाक, जनगणना, बीमा माप एवं मार, निर्वाचन आदि।

समवर्ती सूची म 19 विषय थ । इनम् प्रमुख थे—दीवानी एव फीजवारी विभिया, बनानिक एवं श्रीयोगिक स्रोध, मूल्य नियानण असिक एवं स्वामिया है सम्ब घ तथा आर्थिक एव सामाजिक नियोजन ।

भा तीय सूची म 94 विषय थे। जवाहरणाय—चाति एव व्यवस्था, याय-मसासन, जेल, भू-राजस्व, कृपि, स्थानीय द्यासन, शिक्षा, रसव एव उद्योग पर्छ।

के द्रीय व्यवस्थापिका को समीय सूची के विषयो म सम्पूष पाक्सितान या उसके किसी माग के लिए विधि बनाने ना पूण अधिकार प्रदान किया गया था। 16 इसी अनुच्छद के अधीन यह व्यवस्था भी की गयी थी कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय हिता भी रक्षा एव मुरक्षा, भाषिक एव वित्तीय स्थिरता तथा सम वय एव नियोजन हेतु कजीव व्यवस्थापिका का संधीय सूची ने अतिरिक्त अय विषया पर नी विधि बनान का अधिकार होगा । विसी प्रान्तीय व्यवस्थापिका द्वारा प्रस्ताव पाण्ति करके राजीय

7

पूर्वो पाक्तितान स्वतः व हा गया है और अब वंगला देश क रूप म पूष्ण प्रमृत्व-65 Third Schedule of the Constitution of Pakistan 66 अनुच्छद 131

व्यवस्थापिका का विसी विषय के नियमन का अधिकार प्रदान किय जान पर र त्राव व्यवस्थापिका उस सम्बाध म विधि निमाण-कर सकती थी। परतु एसी विधिवा को प्रातीय व्यवस्थापिकाएँ सवाधित या समाप्त भी कर सकती थी। राजपानी क्षेत्रा— इस्लामाबाद एव ढाका—के लिए वे द्रीय व्यवस्थापिका को संपीय विषया क अविधिक्त सभी विषया म विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त था।

समवर्ती विषया सम्बंधी विधिया से कहीय एव प्रातीय विधिया के सम्बंध में विरोध एव असगति की दक्षा म के द्रीय विधि माय होती थी और प्रातीय विधि उस सीमा तक अवैध होती थी जहाँ तक वह के द्रीय विधि के विरुद्ध होती थी। कि हसी क्यवस्थापिका की विधि-निमाण का अधिकार है या नहीं, इसका निणय करने का अधिकार स्वय व्यवस्थापिका को या और तत्सम्य धी निणय को इस आधार पर कि सदन को उक्त विधि के निर्माण का अधिकार नहीं था, चुनौती नहीं दी जा मकती थी।

के द्वीय व्यवस्थापिका का किसी सीध या सम शीत की क्रियानित करने हर्ष विधि बताने का अधिकार था, मले ही वह विधि किसी प्रान्तीय विषय सही सम्बीधित क्यों न हो। परातु एसी विधि के निर्माण से पूव काद्र को प्रान्तीय गवनरां संपूव परामण करना आवश्यक था।

कायपालिका बिक्त विधायी बिक्त की सहयायी (co-extensive) थी अर्पात जो विधि जिस विधानमण्डल द्वारा निर्मित की जाती थी, उसी कायपालिका द्वारा उसे निर्मावित भी किया जाता था। परतु सविधान द्वारा निम्मलिवित अवस्थाओं में प्रशासनिक क्षेत्र के सम्बच्ध में यह व्यवस्था की गयी थी कि प्रांत सविधान के विच्छ कोई काय नहीं कर सकते थे और न सध की कायपालिका द्वार्क्त के नियावित कर में वाधक होई को स्वावित कर सकते थे और न सध की कायपालिका द्वार्क्त की तिस्वावित करने में वाधक ही ही सकते था।

(1) बाह्य आक्रमण एव आ तरिक अवान्ति से प्राप्ता की रक्षा करना सधीय घासन का कतव्य था। इसके अतिरिक्त सधीय बासन व्यवस्था का यह भी वायित था कि प्राप्तीय बासन सकट-काल के अतिरिक्त सविधान के अनुसार सवास्ति हाता रहे।

(2) प्रातीय कायपालिका घांक ने इस प्रकार प्रयुक्त किय जान की व्यवस्था यी कि संघीय अधिनियमा का पालन होता रहे और संघ की कायपालिका चर्कि क किया चयन में कोई बाधा भी उत्पन्न न हो।

के द्वीय कायपालिका को उपयुक्त उहेरथों के लिए प्रात्ता को आवश्यक निर्देश देने का अधिकार था। इसके अतिरिक्त, के दीय कायपालिका को प्रातों को राष्ट्रीय ^{एव} सनिक महत्व के राजमार्गों के निर्माण एवं निरीक्षण, प्रातों में रलवे एवं रेलव मार्ग की सुरक्षा, पाकिस्तान या उसके किसी मार्ग में शांति एवं आर्थिक जीवन व लिए

⁶⁷ अनुच्छेद 134

सक्ट उत्पन्न होने पर प्रान्तीय कायपालिका द्यक्ति के प्रयोग एव समवर्ती सूची सम्बन्धी किसी विधि को प्रान्त म त्रियाचयन के सम्बन्ध म निर्देश दन का अधिकार था।

प्राता को ने द्वीय सासन की अनुमति के बिना विदेशा सं ऋण लेन का अधिकार प्राप्त नहीं था। 68 के द्वीय व्यवस्थापिका को प्रान्तो को आर्थिक अनुदान प्रदान करने का अधिकार था। 68 सिविधान द्वारा 'राष्ट्रीय वित्त आयोग' की स्थापना भी गयी थी। आयोग राष्ट्रपति का आय कर, निगम-वर, विश्वी एक खरीद-कर, जूट एव प्रपास पर आयत-कर एव राष्ट्रपति द्वारा धापित अ य किसी कर से होन वाली आय का प्राता एव के द्वा म वितरण करने के सम्ब ध म परामदा देता था।

पाकिस्तान के सर्वोच्च यायालय का वे द्वीय एव प्रातीय शासना के मध्य उत्पन्न हान वाले विवादा म मीलिक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया था।

सविधान म मछोधन के त्रीय व्यवस्थापिका द्वारा ही सम्भव था। सवैधानिक सदोधन राष्ट्रीय समा द्वारा कुल सवस्था के वा तिहाई बहुमत द्वारा पारित होने पर राष्ट्रपति की स्वीकृति हतु रक्षा जाता था और राष्ट्रपति का सबधानिक सदाधन को उसके समक्ष प्रस्तुत हाने के तीस दिन के भीतर स्वीकृत या अस्वीकृत करने या राष्ट्रीय समा को पुनर्विचार हुँ सुन्दानिक का अधिकार या। सशोधन के प्रप्ट्रपति हारा अस्वी कृत किय जाने की दशा म राष्ट्रीय समा का उस पर पुनर्विचार का अधिकार या। साधन के स्वीधन तहित अपया बिना सद्योवन के कुल सवस्था के तीन चौथाई बहुमत स्वाधन के सधीधन तहित अपया बिना सद्योवन के कुल सवस्था के तीन चौथाई बहुमत स्वाधन के सधीधन तहित अपया बिना सद्योवन के सुन्दा सहस्ता किय जाने की आवव्यकता नहीं हाती थी। यदि राष्ट्रपति उस पुन अस्वीकृत करता था अथवा कुछ सद्योधन प्रस्तावित करता था और राष्ट्रपति कम पुन 2/3 या 3/4 बहुमत से सद्योधन या विना सद्योधन के पार्टित करके राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करती थी तो राष्ट्रपति को 10 दिन के भीतर सद्याधन को स्वीकृत करने या जननत सप्रह के लिए प्रचारित करने आधकार प्रसान निया गया। प्राचो की सीमाओं म सद्योधन सम्बर्धित करने पार्थन नहीं स्वाधन के स्वीकृत करने वही था। विवास के 2/3 बहुमत की स्वीकृति के विना सम्मव नहीं था। वि

राष्ट्रपति को वाह्य आत्रमण या आत्तरिक विद्वाह अथवा आधिक सकट या उसकी सम्भावना पर पाकिस्तान या उसके किसी भाग म सकट-काल की घोषणा करन का अधिकार प्राप्त था। इसके फलस्वरूप ने द्वीय व्यवस्थापिका को सभी विषयो पर विधि बनान एव अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार प्राप्त हा जाता था।

पाकिस्तान के सधीय शासन को कनाडा एव भारत के सधीय नमून पर काफी शक्तिशाली बनाया गया था। भारत शासन अधिनियम (1935) में के द्रीकरण की प्रवित्त पाकिस्तान की सधीय व्यवस्था में स्पष्ट थी। सघनाद की तीन प्रमुख विशेष

⁶⁸ अनुच्छेद 14

⁶⁹ जनुष्छेद 138

⁷⁰ अनुच्छेद 210

ताएँ-सविधान की सर्वाच्चता, शक्तिया का विभाजन आर केंद्र एवं शाती में विवाद की स्थिति में निणय दने के लिए सर्वोच्च यायालय-पाकिस्तानी सधीय व्यवस्था म थी । पर तु पानिस्तान की अस्थिर आ तरिक राजनीति, अ तरराष्ट्रीय राजनीति एव प्रातीयता की भावना के द्रीकरण के लिए उत्तरदायी थी। प्रातीयता एव क्षप्रीयता की मावना भी पानिस्तान में काफी उग्र थी। पूर्वी पाकिस्तान (अब वंगला देश) ने प्रारम्म से ही पश्चिमी पाकिस्तान के प्रमुख का विरोध किया था । फलस्वरूप दो राजधानियो-डाका एव इस्लामाबाद-की व्यवस्था की गयी थी। ढाका को पूर्वी पाकिस्तान की दूसरी राजधानी बनाया गया था। बगाली एव उर्द को राष्ट्रीय भाषा वताया गया । पूर्वी पाकिस्तान को राष्ट्रीय समा म प्रतिनिधित्व दिया गया था और के द्रीय शासन के सभी क्षेत्रों म जहां तक सम्भव हो सके दोना प्रातों की हिन्दि स समानता की व्यवस्था की गयी थी। य पर तु बगाली राष्ट्रीयता की भावना को दबाया न जा सका और मुस्लिम साम्प्रदायिकता के आधार पर निर्मित पाकिस्तानी सध दीपजीवी न हो सका । पूर्वी पाकिस्तान की उपेक्षा एव आधिक शोपण ने उस प्रदश के बगालियों में विना किसी भेदमाव के सास्कृतिक एवं भाषायी एक्ता उत्पन की जी साम्प्रदायिक सुदृढता (communal solidarity) से कही अधिक दृढ प्रमाणित हुई । पूर्वी पाकिस्तान ने स्वत त्रता के लिए चिरस्मरणीय संघप किया और वह बगली देश के रूप में एक स्वतान राष्ट्र बन गया।

युगोस्लाविया की सघीय व्यवस्था

पूर्यास्लाविया सधीय राज्य है। समाजवादी देश होने के कारण पूर्यास्ताविया की साथिय व्यवस्था परिचमी लोकत त्रीय सधीय देशो की व्यवस्था सिन ते हैं। पूर्यो स्ताविया के सख में 6 इकाइया हैं। "इ ह सधीय समाजवादी गणराज्य की सजा दी जाती है। यूगोस्ताविया म सब, कोट स्त्रोवाक, मेसीडोनियन एव मोटोनीग्री गाम्क पात्रा हो। यूगोस्ताविया म सब, कोट स्त्रोवाक, ह्योरियन, स्त्रोवाक, वलोरियन, चैंक एव इटालियन मी पाय जात है। अत यूगोस्त्राविया बहुराष्ट्रजातीय राज्य (multi national state) है। सब जातिया की मापा एक सी है अत समी स्त्राविया (nationalities) बहुर यूगोस्त्राव समाज की सदस है। यूगोस्त्राविया एतिहासिक परिस्थितियों म एव विभिन्न राष्ट्रा म इनका विकास हुआ है। प्राथित प्राप्ताविया म तीन प्रमुख धर्माववर्यों है। इस्त्राम के बितरिक्त दी ईसाई सम्प्र

⁷¹ अनुच्छेद 16

⁷² सर्विया (Servia), नोटिया (Croatia) बासनिया हुर्जेपाविना (Bosnia Herzegovina) स्लावना (Slovenia), मसीडोनिया (Macedonia), एव मा टोनीग्रा (Montenegro) । सर्विया वे गणराज्य य वोजवाडिना (Voyvodina) एव नोसाची मितोहिया (Kosovo Metohia) नामण दो स्यसासित प्राप्त ह ।

दाय है। 1929 ई म सब, कोट एव स्लावा न अपन राज्य को ग्रूपोस्लाविया मे परिवर्तित कर दिया था। इसी वप आ तरिक समस्याओं के कारण राजा अलेक्जेण्डर प्रथम
ने ससद का मग करके निर्कुश ज्ञासन की स्थापना कर वी लेकिन 1934 ई म
राजा की हत्या कर दो गयी। 1934 ई से 1941 ई तक रीजेन्सी का ज्ञासन रहा।
युद्ध काल म जमनी एव इटली के दवाव म आकर यूगोस्लाविया ने धुरी राष्ट्रा के साथ
एक अपमानजनक सि ध की थी जिसके वो दिन पश्चात अर्थात 27 मान, 1941 ई
को साम्यवादी दल आर उसके नेता टीटो के नेतृत्व म जनता न कार्ति प्रारम्भ कर
दी थी। देश की रक्षा को साम्यवादी दल ने एकसान लक्ष्य घोषित किया था। दीधकालीन मुक्ति आग्दोलन का सुन्पात हुआ। जमनी के पराजित हाने पर 7 मान,
1945 ई को माशल टीटो की अध्यक्षता म नवीन सरकार की स्थापना हुई और
सविधान सभा की स्थापना नवस्वर 1945 ई म की गयी। यूगोस्लाविया का प्रथम
सविधान 31 जनवरी, 1946 ई को लागू हुआ। हितीय की 1953 ई म एव तृतीय
की 7 अप्रैल, 1963 ई को स्वीकार किया गया था। तृतीय सविधान मे यूगोस्लाविया
का नाम समाजवादी मधीय गणराज्य कर दिया गया।

यूगास्लाविया सघीय गणराज्य है। राष्ट्रजातिया को अपनी मानुभाषा ने प्रयोग की स्वत त्रता है। सथीय राज्य हान के साय य्योस्लाविया श्रमिका का एक सामाजिक राजनीतिक समुदाय भी है। 1953 ई के सविधान द्वारा एकता पर अधिक वर दिया गया था और गणराज्या के अधिकारो को सविधान या विधि द्वारा सीमित नहीं किया गया है। साथ ही साथ सविधान द्वारा गणराज्या के सुनिश्चत अधिकारो एव वायित्वा की स्पट व्यारया की गयी है। प्रत्येक गणराज्य स्वायत प्रातो, जिलो एव कम्यूना म विभाजित है। सघीय सविधान की अपेक्षा प्रत्येक गणराज्य का अपना सविधान ह। गणत नीय शासनो द्वारा अपने अधिकारो एव सत्य्वा का सघीय सविधान, सघीय कानूना एव अपन सविधान के अत्यात उपभाग किया जाता है। प्रत्येक गणराज्य को समान स्वत्य तता प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति एव प्रत्येक राष्ट्र विकार के स्वत र एव स्व-विकास के अविकार ह। इसके साथ सामाजिक जीवन से सम्विधत सामाय हितो के प्रस्ता रर सभी गणराज्य परस्पर पूण सहयोग करते है।

सम्भूण समाज से सम्बिधत काया को ही सभीय खासन की साथा गया ह । श्रेष सभी विषय गणराज्या एव स्वायत प्राता का प्रदान किये गये हैं। सधीय शानन को निम्न मामलो म पूण क्षेत्राधिकार प्राप्त ह । ³ यूगोस्ताविया की स्वत त्रता एव सीमाजा की रक्षा, सेनाजा का सगठन एव राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रबच्च सविजान की सुरक्षा की ब्यवस्था वैदेशिक सम्ब य, सिथ्या, युद्ध तथा खाति, नागरिकता, सधीय सगठन और दायित्व का सम्यादन एव सधीय विषया का त्रिया व्यव ।

सध का निम्नलिखित मामला से सम्बन्धित व्यापक विधियों के निमाण का

⁷³ अनुच्छेद 160, माग 2, अध्याय 🛭

अधिकार भी दिया गया है 🕈 सामाजिक सम्पत्ति, सम्पत्ति सम्ब घी अधिकार, मुद्रा, चुगी, विक्रिंग, मार एव नाप, पेटेण्ट, कॉपीराइट, यातायात नियम, मतदान, पीजदारी विधि, सावजनिक सुरक्षा, अस्य शस्त्र, व्यापारिक मामला का गठन, नागरिक सुरक्षा, प्रशासकीय एव "यायिक विवाद, जादि ।

व्यापारिक एव श्रमिक सगठना, श्रमिक एव औद्योगिक सुरक्षा, सावजनिक थम, वजट वन, जलीय यातायात, सामाजिक नियोजन, यातायात, प्रस, नागरिक समुदाया आदि के सम्बाध म मूल विधिया के निर्माण का भी अधिकार सथ की है। समी मामला स सम्बन्धित सामा य विधिया का निर्माण भी सबीय क्षेत्राधिकार के जधीन है।

सघीय सभा (Federal Assembly) सत्ता का सर्वाच्च अग है। सघीय शक्तिया एव अधिकारो का इसी के द्वारा प्रयोग किया जाता है। सधीय सभा को प्रत्यक्षत सविधान म सशोधन करने, सधीय विधियो को पारित करन, जनमत-सप्रह करान, सघीय विधिया की व्यारया करने एव क्षमादान करने का अधिकार है। सघीय सभा द्वारा वजट (वार्षिक आय-व्यय विवरण) एव युगोस्लाविया के समाज की योजना को भी स्वीकृत किया जाता है। देश एव विदेश-तीति के मूल सिद्धान्ता को भी यही समा निर्धारित करती है। इस समा को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सघीय कायकारिणी परिपद के सदस्यो तथा यायाधीशा को निर्वाचित एव पदच्युत करन क भी अधिकार है। इसके पाच सदन है राष्ट्र-जातीय सदन, 25 आर्थिक सदन, शिक्षा एव सास्कृतिक सदन कल्याण एव स्वास्थ्य सदन एव राजनीतिक मगठन सदन । राष्ट्-जातीय सदन के अतिरिक्त प्रत्यक सदन की सदस्य सरया 120 है।

'राष्ट्र-जातीय सदन' (Chamber of Nationalities) गणराज्या का प्रति निधित्व करता है। प्रत्येक गणराज्य द्वारा इस सदन के लिए 20 सदस्यों को एव स्वायत्त प्राप्त द्वारा 10 सदस्या को अपनी समाआ द्वारा निर्वाचित किया जाता है। स्मरणीय है कि आठवे सबधानिक संशाधन के पूर्व संघीय सदम (Federal Cham ber) के अतिरिक्ति राष्ट्र जातीय सदन का भी अस्तित्व था। युगोस्लाविया की संघाय समा के विभिन्न सदन अपन स सम्बंधित विषया पर विधिया का निर्माण करते हैं। सभी सदना की शक्तियाँ समान हैं। राष्ट्र जातीय सदन' को गणराज्या की समानता, व्यक्तियो एव जल्पसंख्यका तथा मणराज्य के संबंधानिक अधिकारा पर विचार करने का एकाविकार प्राप्त था । फेडरल चेम्बर-संघीय सदन-की सभी शक्तियाँ राष्ट्र जातीय सदन को हस्ता तरित कर दी गयी हैं। अत राष्ट्रजातीय सदन की तुलना हम जाय सधीय देशा ने द्वितीय सदना स कर सकत है। इस घटका का प्रतिनिधि

⁷⁴ जनूच्द्रेद 161

आठवें सबधानिक सञाधन द्वारा यह परिवतन हुआ है । इसवे पूर्व राष्ट्र-जातीय सदन को संधीय सदन कहत य ।

सदन मान सकते है। यह सदन इगलैण्ड की लॉडसभा एव भारत की राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि यगोस्लाविया म सभी सदनो को समान शक्तिया प्राप्त है ।

12वें संशोधन द्वारा यगोस्लाविया के सर्विधान में संशोधन की प्रणाली में पूण परिवतन कर दिया गया है। पहले संघीय सभा एव राष्ट्रजातीय समा द्वारा 2/3 बहुमत स सशोधन प्रस्ताव पारित करन पर एव अप सदना द्वारा उसका समर्थन किये जाने पर सविधान में संशोधन प्रमावी होता था। जय तीन सदनी द्वारा संशोधन के सम्बाध में असहमत होन पर जनमत संग्रह की व्यवस्था थी। 12वें सदीधन द्वारा सशाधन प्रणाली सशोधित कर दी गयी है जिसके फलस्वरूप वह पर्याप्त जटिल हो गयी है 1⁷⁶

नवीन सशोधन प्रणाली के जातगत-

- (1) जनमत सग्रह की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।
- (2) सविधान म संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार 30 संघीय सदस्यो. एक सदन, गणराज्यों के राष्ट्रपति एवं संघीय कायकारिणी परिषद की प्रदान किया गया है।
- (3) संशोधन क सम्बाध में प्रत्येक सदन के द्वारा पृथक रूप से निणय लेन की व्यवस्थानी गयी है।
- (4) राष्ट्रजातीय सदन एव दो अन्य सदनो द्वारा सशोधन प्रस्ताव 2/3 बहुमत संस्वीकार कर लिय जाने पर स्वीकृत माना जाता है । यदि निरुतर दो विवादों के पश्चात भी राष्ट्रजातीय सदन एवं आय दो सदन किसी निणय पर नहीं पहुँचते तो जागामी एक वर्ष तक सक्षोधन पर पून विचार नहीं हो सकता।
- (5) सबैधानिक सञाधन सम्बाधी प्रस्ताव स्वीकृत होने पर राष्ट्रजातीय सदन द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाता है और उसे जनता के समक्ष विचाराथ प्रस्तृत रिया जाता है। सशोधन पर श्रमिका के सदन एव सामाजिक राजनीतिक सदन द्वारा इगढ़ परचात विचार होता है और दोना सदन अपना मत देते है। तत्पश्चात राष्ट्रजारीय सदन को सविधान म संशोधन का प्रस्ताव रखने का अधिकार है। यदि गद्रना अ सरोधन पर मतैवय नहीं होता ता नभी सदना की संयुक्त समिति का निमाण रिकार जाता है। यदि उसना निषय मा य नहीं होता तो राष्ट्रजातीय सदन एवं 🐔 🗷 सदनो द्वारा संशोधन स्वीकृत होने पर पारित माना जाता है।

उपर्युक्त सशोधन प्रणाली म सशोधन के लिए गणराज्या एव 🗠 🛩 🛩 सदन-राष्ट्रजातीय सदन-की स्वीकृति अनिवाय है। यह स्कूर -अवस्था है।

Amendment XII, Quoted Constitution of Yungana 76

स्ट्रांग के अनुसार यूगोस्लाविया रूस की मीति एक समाजवादी दश है परनु उसने सविधान का सधीय स्वरूप इस वात का राचक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार नवीन उद्देश्या के लिए पूरान तरीना ना प्रयोग निया जा सनता है।" यूगोस्लाविया म संघीय शासन के तीना सत्व-सविधान की सर्वोश्चता, शक्तिनिवनाक एव सबैधानिक 'यायालय-पाय जात हैं। परन्त एवदलीय व्यवस्था के कारण सपीय शासा बहुत कुछ एकात्मक वन गया है। साम्यवादी दत का एकछत्र राज्य एवं माप्तल टीटो साम्यवादी दल का एकछत्र नता है। सभी संवधानिक व्यवस्थाएँ व्यवहार म साम्यवादी दल की लावत त्रीय वे द्रीकरण की नीति पर आधारित हैं जिसका सहज अप यह है कि वहाँ सत्ता का पूण के दीकरण ह और दल के चोटी के नेताओ म सता का अधिष्ठान है। युगोस्ताविया मोवियत इस की आंति का राजनीतिक सप है जिसम घटको को पर्याप्त सास्कृतिक स्वायत्तता प्राप्त है । यह पश्चिमी ढग का राजनीतिक सघ नहीं है अपित एक सास्कृतिक सद्य है।

भारतीय बचीय व्यवस्था

मारत का नवीन सविधान सधीय दासन की स्थापना करता है। भारत जर्म विशाल, बहुमापी, मित्र मित्र संस्कृतिया और विभिन्न धर्मात्यायिया एव आर्थिक क्षेत्रो वाले देश के लिए सधीय व्यवस्था ही एकमात्र उपयक्त व्यवस्था हा सकती है। सविधान निर्माताओं ने इस सत्य के अनुसार ही सधीय व्यवस्था की स्थापना की है। भारतीय संघीय व्यवस्था का विकास विशेष परिस्थितिया म हुआ है। भारत म संघीय ासन का विचार 1919 ई से बहुत अधिक पुराना नहीं है। मोण्टेग्यू चम्सफोड रिपोट मे इसका उल्लंख या। 8 लेकिन इससे पूर्व महाराजा गामकवाड ने लॉड वेम्सफोड की 1918 ई में भानी सुधारा के रूप सं संघीय शासन का सुभाव दिया या। है भारतीय विधान-परिषद के अध्यक्ष सर फ्रेडरिक ह्वाइट (Sir Frederick Whyte) एवं संपुक्त प्राप्त के गवनर सर मेलकोस हेली ने भारतीय राजनीति की समस्या के समाधान के रूप में संघीय शासन की स्थापना का प्रस्ताव रखा था 1⁸⁰ नहरू कमेटी ने भी कुछ स देह व्यक्त करते हुए सध शासन की स्थापना का सुभाव दिया था। नेहरू कमेटी ने अपने प्रतिवदन म प्रातीय शासनो को पर्याप्त शक्ति प्रदान की थी परत उहे के द्रीय नियात्रण से वहत अधिक स्वतात्रता प्रदान नहां की थी। 81 सार्यन कमीशन न अपने प्रतिवेदन म ऐसी शासन-व्यवस्था के प्रारम्म का सुकाव दिया था जिसकी परिणिति भारत के बहद् सघ म हाती। परातु संघीय शासन का विचार गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही ठीस रूप धारण कर सका था। देशी नरंगा ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन म

⁷⁷

Strong, C F op sit p 130
Banerjee Indian Constitutional Documents Vol III p 225, fn l 78

Document No 52 lbtd p 362
Sharma M P The Government of Indian Republic 1965, p 76
Pylee, M V Constitutional Government in India, 1965 p 91 80

सघीय शासन ने विचार का समथन किया था। वडौदा के प्रतिनिधि⁸⁸ एव महाराजा वीकानेर ने सर तेज बहादर सप्र के सधीय व्यवस्था की स्थापना के विचार का समयन किया था। 183 महातमा गांची ने काग्रेस के दृष्टिकाण का उपस्थित करते हए कहा था कि देश का मानी सनिधान संघीय होना चाहिए तथा भारतीया के हित की सरक्षा हेत जविराष्ट्र इस्तिया घटका में अधिष्ठित होनी चाहिए 184 गोलमेज सम्मेलन के दौरान संघीय शासन के विचार का सहसा उदय हुआ था। वहत से सदस्य उसके सैद्धान्तिक अथ एव परिणामों की कल्पना तक न कर सके थे। इसके अतिरिक्त, कुछ सदस्य सघीय जासन के प्रति अत्यधिक स देहशील थे। मुस्लिम लीग भी सघीय शासन के ही पक्ष में थी परन्तु वे कमजोर सधीय शासन के समयक थे और उन्होंने अवशिष्ट शक्तिया प्राता को देन का समयन किया था। 8 सर मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के अध्यक्षीय पद से भाषण देते हुए कहा था कि "स्वशासित भारत के लिए एकात्मक व्यवस्था उपयक्त नही है।" अत[े] उहाने संघीय शासन का समयन किया था। ⁸⁶ भार-तीय उदारबादी एवं हिन्द राष्ट्रवादी सघीय व्यवस्था के सम्बाध म नेहरू कमेटी के द्वारा व्यक्त विवारी सं सहमत थे।⁸⁷

गोलमेज सम्मेलनो का परिणाम भारत शासन अधिनियम, 1935 ई के रूप में सामने जाया है। स्मरणीय है कि 1935 ई के सर्विधान तक भारत म एकात्मक शासन था । सम्पूर्ण सत्ता जिटिश जाउन मे अधिष्ठित थी और सपरिषद गवनर-जनरल नाउन के नाम पर भारत का शासन चलाता था। भारत शासन अधिनियम, 1935 ई क द्वारा प्रातो म स्वशासन तथा के द्र में ब्रिटिश मारत एवं देशी रियासतों के सच की व्यवस्था की गयी थी। 1935 ई के अधिनियम द्वारा व्यक्त संघीय व्यवस्था में संघ शासन की तीन विशेषताएँ---लिखित सविधान, शक्तिया का विमाजन एवं सर्वोच्च पायालय-क होते हुए भी संघीय शासन के सार-प्रान्तीय स्थायत्तता-का अभाव था । गवनर जनरल को विशेष शक्तिया एव अधिकार प्रदान किये गय थे । गवनर-जनरल को व्यवस्थापिका को भग करके सभी शक्तिया अपने हाथ म लेने का अधि-कार था। इसके अतिरिक्त, उसे सकटकालीन शक्तिया प्रदान की गयी थी जिनकी तीव आलाचना की गयी। सधीय व्यवस्था को राष्ट्रीय एव साम्प्रदायिक नेतामा द्वारा अस्वीकार कर दिया था । द्वितीय विश्व-यद्ध जनित परिस्थितियो एव देशी नरेशो के असहयोग के कारण इस किया वित नहीं किया जा सका।

द्वितीय विश्व युद्ध ने पश्चात भारतीय राजनीतिक गतिरोध के समाधान हेत

Banerjee A C Indian Constitutional Documents, Vol III, p 364 First Round Table Conference Proceedings p 28 Banerjee A C Ibid, Introduction, p XVI Refer to Jinnah's Fourteen Points 82 83

⁸⁴ 85

The Indian Annual Register, July Dec 1930 Vol II, pp 338 41 86 Asycr, S P Essays on Indian Federalism, p 13 87

लीय मिशन के समक्ष प्रमुख समस्याएँ थी पाकिस्तान, देशी रियासते एव जल्पस्पकों की समस्या । कविस भारत ने विभाजन के विरुद्ध थी । मुस्लिम लीग पानिस्तान की स्थापना पर हढ थी । अत मिशन न निभूत्री सपनाद की योजना प्रस्तुत की । इक अस्वात को मिश्र अस्तुत की । इक अस्वात को मिश्र अस्तुत की । इक अस्वात के प्रोप साम का मुश्र के होने का अपिकार या । स्मरणीय है वि केविनेट मिश्रन न पाकिस्तान की मींग की प्रतक्ष कर पा अस्वीकार कर दिया था । उसकी घारणा थी कि पानिस्तान के निर्माण से देश की सुरक्षा कतरे म पड जायगी । लेकिन मिश्रन योजना प्रियानित न हो सकी ।

ब्रिटिश सरकार ने मित्रमण्डलीय मिक्षन (1946) को मारत नेजा था। मित्रमण्ड

मुस्लिम लीग ने पाबिस्तान के लिए सीधी कायवाही प्रारम कर दी। कांग्रस तथा लीग में समभीते के कोई आसार नहीं थे। इसी समय यारतीय नीसना ने भी विद्रोह कर दिया था। अत ब्रिटिश सासन ने मारत छोड़ने के अपन निजय की पोपणा की। लॉड माउप्टेटन ने मारत विमाजन को योजना प्रस्तुत की जिसे प्रमेस एव लीग दोग ने स्वीकार कर लिया। 15 अगस्त, 1947 नो देश विमाजित हुआ और दो स्वत न उपनिवेद्या का जम हुआ। सम्पूण देश साम्प्रदायिक उपदावा एव हिंसा के दावानत में जल रहा था। पाकिस्तान के निर्माण ने देश में विपटन को वल दिया। देशी रियासते ब्रिटिश शासन ने हटने से स्वत न हा गयी थी। सरदार पटेत की दूरविंशत एव हडता ने कारण मारत का विघटन होत होते वच गया। देशी रियासतो के विवयन एव एकोकरण के फलस्वरूप 562 देशी रियासतो के स्थान पर केदत 15 देशी रियासते ही रह गयी और दह ब्रिटिश मारत के प्रतिस्ता ने मीति मारतीय स्था म

केविनेट मिशन योजना के अत्तगत सविधान समा ने दिसम्बर 1946 ई म काय प्रारम्भ कर दिया था। मुस्लिम लीग ने असह्याग किया। मारत के स्वत त्र हीने पर मारतीय प्रदेश की सविधान समा ने काय प्रारम्भ किया। सविधान समा ने सद स्या पर देश विभाजन एव विधटन की पिरिस्थितिया का प्रमाव पडा था। वे मविध्य म मारत के विधटित हो जाने की चिता सं यस्त थे, फसस्वरूप उहोन सपीय णावन की अरक्षाक्रत अधिक गरिकाशी बनाया।

संधीय व्यवस्था की तीनो विशेषताएँ—सविधान की सर्वोच्चता, शक्तियो को विमाजन एव सर्वोच्च यायालय—सारतीय सम मं भी पायी जातो है। मारत की सविधान लिखित एव कठोर है। सविधान के संधीय भाषा मं संशोधन के लिए एज्या की स्वीकृति आवश्यक है। के इ. एवं राज्यों मं शक्तिया का स्मप्ट विमाजन तीन सूचियों—के द्रीय, समवर्ती एव राज्य मुची—द्वारा किया जाता है। अवधिष्ट शक्तियाँ के द्वारा को प्रवास की व्याख्य करें विधान की व्याख्या करें एवं सिवधान की व्याख्या करें एवं सिवधान की व्याख्या करें एवं सिवधान विशेषी विधान को अवधानिक घोषित करने का अधिकार प्राप्त है तथा के द एवं राज्या व परस्पर राज्या मं होने वालं विवादों मं सर्वोच्च गांगालय की

मोलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अत मारत एक सधीय राज्य है।

परन्तु कुछ बिद्धान इस मत से सहमत नहीं है। उदाहरण के लिए, के सी ह्वीपरे के अनुसार भारतीय सघ को अधिक से अधिक अद्ध सधीय राज्य कहा जा सकता है। "यह एकात्मक राज्य है जिसमें कम सधीय तत्व है। यह ऐसा सधीय राज्य नहीं है जिसमें एकात्मक तत्व कम हो। "³⁸⁸ डी एन बन्वर्सों के अनुसार "भारतीय सिवान स्वरूप में सधीय होत हुए भी एकात्मकता से युक्त है। "³⁸⁸ डॉ के पृन संखानम की मुकर्जी इसे असधीय या एकात्मक सिवामा कहते हैं। " डॉ के पृन संखानम की अनुसार भारतीय सधीय राज्य एक सब तो है परन्तु एक विशेष प्रकार का सप है। वे उसे सावमीम सथ (Paramount Federation) कहते हैं। "भारतीय सब को के क्रकृत सम या विकेटिक एकात्मक राज्य की सज्ञा दी जाती है। इन कथनों का अर्थ यह है कि भारतीय सविधान स्वरूप से सधीय है पर तु आत्मा से एकात्मक है। इस कथनों का कर्म यह है कि सारतीय, एकेवकक्षेत्रीविच का मत है कि भारत एक सधीय राज्य है जिसमें राजत्व के लक्षणों (सम्मुल्व छोक्त) का उपभोग केन्द्रीय एक स्थानीय राज्य है जिसमें राजत्व के लक्षणों (सम्मुल्व छोक्त) का उपभोग केन्द्रीय एक स्थानीय राज्य हारा किया जाता है। "

शक्तिशाली के द्व

भारतीय संघीय व्यवस्था मं केंद्रीकरण की अवित्त के पक्ष में निम्नलिखित तक विषे जाते हैं

- (1) मारतीय सविधान भे कनाडा के सविधान की माति 'Union' शब्द का प्रयोग किया गया है न कि 'Federation' का (अनुच्छेद 1)।
- (2) भारतीय ससद को आरतीय सच मे नवीन राज्य को बामिल करने और नवीन राज्यों के निर्माण का अधिकार है (अनुच्छेद 2)। ससद को किसी एक राज्य में से नचे राज्य बनान, दो राज्यी को एक राज्य में सामिल करने, किसी राज्य के साथ किसी क्षेत्र को मिलाने, राज्य का क्षेत्रफल बढाने या घटाने या राज्य की सीमा एव नाम मे परिवतन करने का अधिकार है (अनुच्छेद 3)। परतु उपयुक्ति विषया से सम्बध्धित विशेषका को ससद म प्रस्तुत करने के पूब उन पर राज्यपति की स्वीकृति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, उन राज्यों के भी विवार जात करना आव-

⁸⁸ The Indian Union ' is at most quasi federal almost devolutionary in character a unitary state with subsidiary federal features rather than a federal state with subsidiary unitary features' —Wheare K C Aspects of Indian Constitution, of cit p 50

^{89 &}quot;India's Constitution is federal with a pronounced unitary basis"

—D N Banesjee, 1962 p 114

⁹⁰ It in "unfederal or unitary constitution" — Mukerjee K P Dr, Indian Journal of Political Science, July Sept 1954, p. 177

⁹¹ Santhanam, K. Centre-State Relations, 1960, pp 12-13

⁹² India is undoubtedly a federation in which the attributes of statehood are shared between centre and local state —Alexan drowicz, C. H. Constitutional Development in India, p. 169

स्यक है जिनके क्षेत्रफल एव सीमा मे परिवतन किया जा रहा हो । इस प्रकार राज्या के नाम एव सीमा अथवा क्षेत्र मे परिवतनो को सवधानिक सखोधन सम्बधी व्यव स्थाएँ नहीं माना गया है (अनुच्छेद्व 4) । इसका अथ है कि इस सदम म सशोधन पद्धति (अनुच्छेद्व 368) के उपयोग की आवस्यकता नहीं है । अनुच्छेद्व 2 तथा 3 के अधीन हो 1956 ई से राज्य पुनगठन विधि पारित की गयी थी और बाद म अनेक नवीन राज्यों का निमाण हुआ है ।

(3) के द्र एव राज्यों में शक्तियों का स्पष्ट विमाजन है। के द्रीय सुन्नी के विषयों पर के द्रीय सरकार एवं राज्य सुन्नी के विषया पर राज्यों को विधि निर्माण के अधिकार प्राप्त है। समवर्ती सुन्नी पर के द्र एवं राज्य दोनों को विधि वनाने का अधिकार प्राप्त है पर तु एक ही ऐसे विषय पर यदि के द्र और राज्य ने विधि का निर्माण किया है तो राज्य द्वारा निर्माल किया है तो राज्य द्वारा निर्माल विधि को अपेक्षा के द्रीय विधि माय होगी और राज्य-विधि अस सीमा तक अवैध मानी जायगी जहां तक वह के द्रीय विधि के विषद होती है।

के द्वीय सूची में राज्य सूची की तुलना म अधिक एव महत्वपूण विषय हैं। इसके अतिरिक्त, समवर्ती सूची के विषया पर नी केन्द्र की विधिनिर्माण का अधिकार

प्राप्त है। मारतीय सथ म अवशिष्ट शक्तिया भी केंद्र को प्राप्त है। इसके असिरिक्त, मारतीय ससद को निम्नलिखित अवस्थाओं म राज्य-सूची कें

विषयो पर भी विधि निर्माण का अधिकार है

(i) राज्यसमा द्वारा अपने कुल सदस्यो अथवा उपस्थित सदस्यो के दो तिहाई वहुमत से प्रस्ताव पारित करक राज्य-सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व को घोषित करने पर एक वय के लिए उस विषय पर ससद को विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो आता है (अनुक्छेद 249)।

(11) सक्ट-काल की अवस्था म ससद को राज्य-सूची के किसी मी विषय

पर सम्पूर्ण देश या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है। (अनस्छेद 250)

(m) एक या दो राज्या द्वारा प्राथना करने पर ससद को राज्य मूची क

विषय पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है (अनुच्छेब 252)।

(IV) किसी सिंघ या अन्तर्राष्ट्रीय समझीत के नियाज्यन हेतु झारतीय समद को सम्पूण मारत या उसके किसी एक माग के लिए विधि बनाने का अधिकार

प्राप्त है (अनुन्देद 253)।

(4) सभीय सासन को राज्य प्रधासन पर प्रयाप्त निय वण प्राप्त है। सभीय प्राप्त के विषय ॥ सम्बर्गिय नायगानिका सक्ति के द्वीय सासन प्रण्य राज्यन्त्रीय साम्बर्गियत गांकि राज्य-सासन म निहत है। परातु समवती मूर्चों का प्रधासन सामा चन राज्या के प्रभी है। इसके प्रतिरक्ति, सविभान क अनुसार राज्या द्वारा अपनी भाषपानिका सामा ज्वारा स्वर्णें के स्वर्णें के स्वर्णें के स्वर्णें के स्वर्णें के स्वर्णें स्वर्णें कि स्वर्णें विषय स्वर्णें के स्वर्णें स्वर्णें स्वर्णें विषय स्वर्णें के स्वर्णें स

सपीय प्रशासन मे कोई वाधा न पढे (अनुच्छेद 256)। राष्ट्रीय महत्व के यातायात मार्गों के निर्माण एव उनकी रक्षा तथा राज्या वी सीमा मे रेलवे-यथों की रक्षा के लिए सपीय झासन राज्य शासन को आदेश दें सकता है (अनुच्छेद 257)। यदि किसी राज्य शासन को आदेश दें सकता है (अनुच्छेद 257)। यदि किसी राज्य शासन हारा सपीय विषय से सम्बन्धित सपीय शासन के किसी आदेश का पालन नहीं किया जाता तो राष्ट्रपति को उस राज्य में सविधान की विफलता की पीपणा करके बहा राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार प्राप्त है (अनुच्छेद 365)।

- (5) राष्ट्रपति को ध्यापक सकटकालीन श्रीक्तया प्राप्त है और सकट-काल में देश की ध्यवस्था एकारमक हो जाती है। सकटकालीन घोषणा के पश्चात के द्रीय सरकार राज्य के किसी भी अधिकारी को राज्य की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के सादम में निर्देश दे सकती है। किसी राज्य में सवधानिक विफलता की अवस्था में बहा राष्ट्रपति शासन स्थापित किया जा सकता है (अनुष्केष 353 (क) व 356 (क))।
- (6) ससद को राज्य विधानमण्डल के द्वितीय सदन-विधान परिपद-के सगठन में आमूलबूल परिवतन के अधिकार है (अनुच्छेद 171 (2))।
- (7) केन्द्र की वित्तीय स्थित राज्यों की अपेक्षा हढ है। अधिक आय के स्रोत केन्द्र की प्रदान किये गये हैं। सिवधान द्वारा शिक्त सूचियों के आधार पर राजस्व के स्रोतों का विभाजन किया गया है। यह अस्पष्ट एवं अपूण है। राज्या की कमजोर वित्तीय स्थिति को ध्यान ने रखते हुए सिवधान द्वारा के त्रीय अनुदान की ध्यवस्था की गयी है (अनुख्केद 275 एवं 282)। केन्द्र एवं राज्या के वित्तीय सम्बाध अस्यत जटिल है। केन्द्र द्वारा वित्तीय करों से होने वाली आय के वित्तरण के लिए प्रति पांच वप वाद वित्त आयोंग की निवृक्ति की जाती है।
- (8) सविधान के अनुसार राज्यों की सुरक्षा एवं वाह्य आक्रमण तथा आत्त-िक विद्रोहा से रक्षा करना एवं यह देखना कि सविधान के अनुसार राज्य धासन संचालित हो रहा है, के द्रीय शासन का दायित्व एवं कतच्य है (अनुच्छेद 355)।
- (9) जारत में अमेरिका की जीति दोहरी नागरिकता एव दोहरी चायपालिका नहीं है। न राज्यों के पृथक सविधान ही है, न पृथक निर्वाचन आयोग है। अपितु राज्या एव सधीय निर्वाचन के लिए एक ही निर्याचन आयोग है। यारत में एकल नागरिकता एव पायपालिका है। के द्वीय एव राज्या के वित्त पर नियंचण रखने के लिए कम्प्ट्रोजर एव आडीटर जनक की निमुक्ति पान्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। राज्या के राज्यपाला को राज्यपति द्वारा निमुक्त किया जाता है और उसी ने प्रसादन्यत ये पदान्य रहते हैं। राज्यों के उच्च यायालय राज्य के प्यायालय हैं, परन्तु जनका सगठन सधीय नियय ह। उनके प्यायाधीया की निमुक्ति एव पदच्युति अथवा स्थानान्तरण राज्युति द्वारा किया जाता है (अमुब्देव 217)।
 - (10) अखिल भारतीय सेवाबो— भारतीय प्रवासनिक सेवा (Indian Administrative Service) एव भारतीय पुलिस सेवा (Indian Police Ser

vice)—के सदस्य राज्यों में मुख्य-मुख्य पदो पर काय करते हैं। के द्रीय दासन की ऐसी अन्य सेवाजी की स्थापना का भी अधिकार है (अनुच्छेद 312)।

आलोचको का मत है कि उपर्युक्त सवधानिक के द्रोकरण दलीय व्यवस्था एवं नियोजन के द्वारा और भी अधिक कठोर वन गया है। एक ही दल का केट एवं राज्यों म शासन होने के कारण तथा दलीय अनुसासन एवं नियानण के माध्यम स केंद्र का निय त्रण के साध्यम स केंद्र का निय त्रण के साध्यम स केंद्र का निय त्रण के साध्यम स केंद्र का निय त्रण और अधिक हो गया है। विश्वत 25 वर्षों में केंद्र में सम्प्रण कात तक एक पत्र अधिकाश का समय तक अधिकतर राज्यों में काग्नेस का एकछन राज्य रहा है। काश्य हाईकिसायको द्वारा काग्नेसी राज्यों के मुक्समित्री एवं मित्रमण्डल के सदस्या में निगुक्ति, उनमें विभागों के विभाजन एवं नीतिया आदि के सम्बाध में निगय तिये वार्वे हैं। राज्य शासन के वारे में अतिया निगय तेने का काग्नेस ससदीय दल एवं कावर हाईकिसायको है। एक हो एकाधिकार है। राज्यों के मुक्समानी आये दिन दिस्सी माम तकान का एकाधिकार है। राज्यों के मुक्समानी आये दिन दिस्सी माम तकान है। जिन प्रांतों में काग्नेस से मिन दलों की सरकार वनी है वहीं की स्थिति मिन है। पर तो वे भी अपने प्रसुक्त नहीं वार्वे हैं।

मित है। परातु वे भी अपने प्रमुख दलीय नेताओं के नियानण से मुक्त नहीं होते हैं। नियोजन भारतीय सधीय व्यवस्था मे अत्यधिक के द्रीकरण करने वाला सबस तस्य प्रमाणित हुआ है । योजना आयोग को मारत के 'आर्थिक मरिप्रमण्डल' की सज्ञा दी गयी है। राज्य की पचवर्षीय योजनाएँ योजना आयोग के परामश से तयार की जाती है और वह उनके तिया वयन की भी समीक्षा करता है तथा किसी पृटिया कमी की दशा म राज्य सरकारा को सलाह एव निर्देश देता है। सिद्धा तत यह परामग्र एवं सलाह केवल विचार विमश ही होते है पर तु व्यवहारत वे स्पष्ट निर्देश होते हैं। योजनाओं के लिए योजना-आयोग अनुच्छेद 282 के अधीन आधिक अनुदान प्रदान करता है। फ्लत राज्य योजना आयोग की उपक्षा करने म असमय रहते हैं। 1952 53 ई म अनुच्छेद 282 के अधीन 8 59 करोड़ की धनराधि राज्यों को अनुवान के हुए में दी गयी थी । यह प्रारम्म था । प्रति वर्ष यह राशि बढती गयी । प्रथम पचवर्षीय योजना म 64 03 करोड और द्वितीय पचवर्षीय योजना म 275 करोड रुपये केंद्र हाए योजना पर व्यय ने लिए विभिन्न राज्या को अनुदान-स्वरूप दिये गये थे। अधिकार अनुदान पूरक (matching) अनुदान होते हैं। अ राज्या की वित्तीय स्थिति सुंहर् न हाने के कारण वे ने द्रीय अनुदान पर ही योजना क किया वयन के लिए निमर नरहे हैं। यह सभी अनुदान विनिन्न के द्रीय म वालया द्वारा सम्पादित विये जाते हैं क्वाहि सिद्धातत योजना-आयोग तो नेवल परामशदात्री निवास है, न कि कोई कायकारी निकास । 35

⁹³ नाम्रस हाईनमाण्ड से तात्यय काग्रेस के वरिष्ठ प्रजावनाती दलाय नेताजा स है जो नाप्रेस की विनिध गीयस्थ दतीय सस्याजा व सदस्य हात हैं और इत्रा दल एउ प्रासन पर समान प्रमाव हाता है ।

⁹⁴ Santhanam, L. op at . p 53

⁹⁵ Ibid

नियोजन के सम्बाध म राज्या के सहयोग को प्राप्त करने के लिए कुछ सस्याओं की स्थापना की गयी है । इसमें 'राष्ट्रीय विकास परिपद' (National Development Council) बहुत महत्वपूण है । प्रधानमाणी ही इसका अध्यक्ष होता है और राज्यों के मुख्यमानी इसके सदस्य होते हैं । इस परिपद को कोई विधिक या सबैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है पर्यु इसके निजय के द्वीय एव राज्यों के मन्ति-मण्डलो पर वाधनकारी होते हैं । ऐसे अधिसमय का विकास हुआ है । इस परिपद हारा जनेक बार एसे निजय विवो जाते हैं जिन पर सामाय सधीय विधिक व्यवस्था के अधीन राज्यों एवं के द्वीय विधानमण्डला द्वारा विचार विमा किया जाना चाहिए । सथानम न राष्ट्रीय विकास परिपद को देश की 'सुपर कैंबिनेट' की सजा दी है । हैं

समीक्षा — उपर्युक्त आलोचना मे पर्याप्त सस्य है पर जु के क्रोकरण भारतीय संघीय सिवधन की कोई एकमात्र विश्वयता नहीं है। वे द्वीय शासन की शक्तियों में समी संघीय राज्यों में वृद्धि हुई है। संयुक्त राज्य अमिरका जिसे ह्वीयर सहश विद्वाना द्वारा संघीय शासन का प्रमाणिक उदाहरण माना जाता है, वहां भी संघीय शासन की शक्तिया में असाधारण वृद्धि हुई है। अत भारत इस विश्वय्यापी सामान्य प्रवृत्ति का उपवाद नहीं हो सकता।

भारतीय संघीय संविधान म के द्रीकरण समय की माग है। अत्यधिक के द्रीकरण तो सघवाद के विपरीत होता है पर तु राज्यों की स्वत नता के नाम पर राष्ट्रीय
सुरक्षा को सतर में नहीं डाला जा सकता। सवैधानिक के द्रीकरण, नियोजन एवं दलीय
पद्धति से उत्पन्न के द्रीकरण की बाढ पर भाषावार प्रातों के निर्माण—भाषावार
(Linguism)—न रोक लगायी है। अनुष्डंद 2 और 3 के अन्तवत ससद का राज्यों
के नाम, क्षेत्र, सीमा आदि में परिवतन का अधिकार देकर सविधान सभा ने बुद्धिमानी
की है। सविधान निमाण के समय भाषायी प्रातों के निर्माण का प्रजन हल नहीं हो
पाया था अत बाद में भाषावार प्राता के सरस्ताधूवक निर्माण के लिए उक्त उपबन्ध
किया गया। स्मर्काय है कि काग्रेस भाषावार प्रातों के निर्माण के स्तु हल नहीं हो
पाया था अत बाद में भाषावार प्राता के सरस्ताधूवक निर्माण के लिए उक्त उपबन्ध
किया गया। स्मर्काय है कि काग्रेस भाषावार प्रातों के निर्माण के स्तु हल सहाय
थी। 1956 ई मे जनता के विरोध के सामने के द्रीय शासन को भुकता पदा और
राज्यों का पुनाठन हुआ। आ प्र, सहाराष्ट्र एव गुजरात का निर्माण और पजाब का
सिमालन मापावार का ही परिणाम है। अत के द्रीकरण के विरुद्ध भाषावार एक
पक्तिशाली तत्व प्रमाणित हुआ है।

मारतीय संघीय व्यवस्था को कुछ विचारका^श न सहयोगी संघवाद को सना दो है। यह विस्तेषण काफी तकपूण हं। संस्पूण सविधान म अनेक सहयोगी तत्व विद्यमान हैं। वित्त-प्रायोग (अनुच्छेद 280), अन्त राज्यीय जंसीय विवाद निणय की व्यवस्या (अनुच्छेद 262), दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक मेवा आयोग की स्यापना

⁹⁶ Santhanam, K., p 47

⁷ Aiyer S P and Mehta Usha Essays on Indian Federalism, 1964, pp 114 134

(अनुच्छेद 252 (2) और (3)), जन्त राज्यीय विवादा ने समन्वय हुनु अन्त राज्या पिराद की स्थापना (अनुच्छेद 263), अधिल मारतीय नवाएँ (अनुच्छेद 312), राज्यें को के द्रीय दायित्वा नो प्रदान करना (अनुच्छेद 258), अन्त राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य म वाधाआ के उम्मलन को व्यवस्था (अनुच्छेद 286, 301, 302 एवं 333), राज्यं को बाह्य आत्रमणा एवं आन्तरित विद्वाहा से रहा। आदि उपय पर व्यवस्थाएं सहयोगी सम्याद के प्रमाण हैं। व्यवहार मं नी ने द्व एवं राज्या के मध्य सहयोग ना विदान में हो रहा है। राज्या म सवयानिक सासन नी असफतता पर राष्ट्रपति गावत नी व्यवस्था प्राच्या परियोग ने साम ने अपने साम ते प्रचान ने साम ने कि दें। अधिकार मामला म के दें ने आवर्षकता से अधिक समन तक राष्ट्रपति धासन का राज्य म कायम नहीं रता है। मारिन वान ने के द्व और राज्य क योच सम्य या को समीहा। करते हुए कहा है कि नारत में सौदेवाज सथवाद (Barganning Federation) है। ध यह मत अधिक प्राप्त नहीं है।

त्रेखक भारतीय सपीय स्पवस्था को अद्ध-सपीय स्पवस्या मानने के लिए तथार नहीं है। सपीय शासन के तीन लक्षण हैं लिंग्नित सविधान, ग्रांक विमानन एवं सर्वोच्च यायालय। भारतीय सप इनकी पूर्ति करता है अब भारत एक नव है। के द्वीय शासन को अपन वायित्व के अनुरूप शक्ति आपत है। आज का प्रिकृतिवानन हर काल के लिए उपपुक्त नहीं हो सकता। अत सामाधिक आवस्यकताओं क अनुसार परिततन अरिक्षत है। भारतीय सप म शक्तिशाली के द्वीय शासन एक एक विविधिक आवस्यकता है। निवल के के का अप शक्ति है। मारतीय सप म शक्ति हों मारतीय राष्ट्र का विघटन। मण के निर्माण म विघटन एव एकीकरण दोनो पद्मिता है मारतीय राष्ट्र का विघटन। मण के निर्माण म विघटन एव एकीकरण दोनो पद्मिता का प्रयोग हुआ है। ब्रिटिश मात्री को, जो एकारमक शासन के अग थे, राज्या के रूप में सप म स्थान दिया गर्या है। विशेषी प्रयोग के स्थान प्रमुखन-स्थान हो। येथी थी। सप म शामिल होने के लिए देशी नरेशों ने प्रवेद-पन्ना पर हस्ताक्षर किये अत देशी रियासती का मारतीय सभ में प्रवेश एकीकरण की प्रणाली का प्रमाण है।

कुछ आलोचका का मत है कि के द्रीय घासन को अपयोग्त द्राक्तियां प्राप्त हैं। व्यावहारिक हृष्टि से के द्रीय सरकार विकास योजनाओं के किया वयन में सफत नहीं हृदें हैं। मुप्तिसिंद अमेरिकी विचारक एपिलवी का मत है कि राज्या की तुलता कर कि कमजोर हैं। उनका कपन है कि 'कोई वढ़ी राष्ट्रीय सरकार जो नस्तुत स्वतंत्र हैं सिद्धातिक हृष्टि से तारत की के द्रीय सरकार के वरावर अधीन दकाइयो पर निवर्ष नहीं करती ।''अविकास-योजनाओं के किया वस्तु से तिपर के राज्या पर निवर्ष हैं। ''आजकल तो के द्रीय व्यवस्था प्रधानमानी के असाधारण व्यक्तित्व के प्रमाव के

⁹⁸ Jones, William Morris The Government and Politics of India, p 141

⁹⁹ Alexandrowicz, C H Constitutional Development in India, p 169 100 Appleby H Paul Public Administration in India—Report of a Survey p 21

कारण चल रही है। मिवष्य मे क्या होगा?" राज्या मे के द्र का कोई अधिकारीमण्डल भी नहीं है जिसके द्वारा वह सकटकालीन शक्तिया का प्रयोग करा सके।
एिक्तियो ने मारतीय सम की शक्ति-विमाजन की भी आलोजना की है। उनकी हिंदि
में सावजनिक स्वास्थ्य एवं महल्ले-पाजन जैसे विषय भी राष्ट्रीय सरकार को सोपने
बाहिए क्योंकि इनका राष्ट्रीय महल्ल है। डा महादेव प्रसाद शर्मा ने इस आलोजना
के सारहील नहीं माना है यथिय यह अवेरिकी मुख्यूमि से प्ररित्त है। उत्तर प्रदेश
से सावलिक ऐपिलवी इस तक से सहमत है कि शिक्ति-विभाजन ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश
में पुनिस बिद्रोह हुआ था। क्या यह राज्यों की कमजोरी का प्रमाण नहीं है ? क्या
यह घटना इस मत का समयन नहीं करती कि के द्र को राज्यों में महत्वपूण स्थानो
पर के द्रीय सुरक्षा दल की दुक्तियाँ स्थायी रूप से तनात कर देनी चाहिए ? लेखक का
मत है कि कुपि, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि विपया को यदि के द्रीय विपय नहीं बनाया
सा सकता तो उन्ह कम से कम समवर्ती सुची में अवस्थ स्थान देना चाहिए। इन
विषयों का राष्ट्रीय महत्व है।

मारतीय समिय व्यवस्था विकास की स्थिति में है और केन्द्र एवं राज्यों के सम्बाध निर्माणावस्था में हैं। 1947 ई की अपक्षा 1972 ई में समीय व्यवस्था एक अधिक वास्तियिक तथ्य है। सधीय व्यवस्था स्वयसाध्य नहीं है अपितु साधन है। साध्य जन कत्याण है। अत आवश्यकता इस बात की है कि कन्नीय शासन को राज्यों के प्रति अपेक्षाञ्चल सहयोगी रुक अपनाना चाहिए और राज्यों को सकीण क्षेत्रीयता एवं माणावाद सं मुक्त होना चाहिए। राज्य्रीय एवं क्षेत्रीय हितों मंस्वस्थ संतुलन ही सुषीय व्यवस्था की सफलता की कजी है।

मलयेशिया एव सघवाद

मलाया मे सपीय व्यवस्था ब्रिटिश शासन की देन है। ब्रिटिश औपनिवैशिक शासन काल में द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात सलाया में सपीय व्यवस्था (1948 हैं) की स्वापना हुई थी। इस समय आर्थिक कारणा की अपेक्षा सुरक्षा की आवस्थनता में सपीय शासन की स्थापना में अधिक योग दिया था। मलाया ब्रिटिश साम्राज्य का एक अग था। इस देश म तीन प्रधान जातिया—सवस, तिथल एव चीनी—निवास करती हैं। सनय मूल निवासी हैं पर तु ने आर्थिक हृष्टि से अविकसित हैं। मलाया म सधीय शासन की स्थापना में बहुजातीयता ने ही केवल योग नही दिया है। दिस्पी एव दिसाण-पूर्वी एश्विया के कीन में 1941 ई के जापानी आत्रमण के समय से सेकर 1954 ई में इच्डोबीन में युद्ध प्रारम्भ होने तक का काल सकट एव समय का काल सह है। इस क्षेत्र के अनेक देशा ने युद्ध, साक्ष्म विद्राहि, विदेशी आक्रमण एव तीज सिनत्य आरोलाने के द्वारा स्वत तता अजित की भी पर तु साम्यवादी आत्रमण तया पिरचन्य साम्राज्यवाद के परिवर्तित रूप के आक्रमण की सम्मावना का भय सदब इन देशा पर

¹⁰¹ डा महादेव प्रसाद सर्मा मारतीय गणतात्र का सविधान, 1959, पृष्ठ 99।

द्याया रहता था। फलत मारत एव मलाया जैसे देशा में इढ सधीय शासन व्यवस्था के अपनाया गया। मलाया की सधीय व्यवस्था के अतमत के द्रीम शासन अविषक होटी-वही रियासते थी। ब्रिटिश शासन मताया प्रदेश में सुल्तानों के माध्यम से शासन करता था। 1946 ई में मताया प्रदेश के स्थानीय ब्रिटिश अधिकारिया एवं मलय राप्ट्रवादियां म राजत व इतन अधिक शिक्त शासी था। कि एकत नीय शासन-व्यवस्था की स्थापना असम्भव थी।

दक्षिण-पूर्वी एशिया मे मलाया भारत की माति एक स्थायी सघीय शासन है। ब्रिटिश काल में स्थापित संघीय व्यवस्था के फलस्वरूप मलामा में विदेशी शासन से राष्ट्रीय सरकार को सरलतापूवक सत्ता का हस्ता तरण सम्मव हो सका था। 31 जगस्त, 1957 ई को मलयेशिया सघ का नवीन सविधान लागू हुआ है। यह सर्वि धान लिखित है। सम की 11 इकाइया है। समीय एव इकाइया की सरकारों के मध्य शक्ति विमाजन के अनुसार मुरय विधायी एव कायपालिका शक्तिया सधीय सरकार को प्रदान की गयी है। राज्य की विधियों एवं सधीय विधियों के मध्य विरोध की अवस्था मे सघीय विधिया मा य हाती है। राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं की राज्य-दाक्ति के विरुद्ध भी क्रियाचित करने का संघीय शासन को अधिकार है। संघीय सविधान में सद्योधन व्यवस्था कठोर है। मलयेशिया की संसद क दाना सदनों की कुल सदस्य सरया के हुँ बहुमत से सशोधन पारित होने पर प्रमावकारी होता है। अमेरिका की माति राज्या द्वारा सशोधन के अनुमोदन एव स्विटजरलण्ड की भाति जनमत सग्रह द्वारा सशोधन की अनिवाय स्वीकृति की व्यवस्था मलयेशिया मे नहीं है। मलयशिया की ससद की सबैधानिक सशोधन के सम्बध मे एकाधिकार प्राप्त है। मलयेशिया की ससद डिसदनात्मक है। प्रथम सदन-दीवान ए रैय्यत-प्रतिनिधि सदन (House of Representatives) के 104 सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति स एकल सदस्यो निर्वाचन क्षेत्रा से चुन जात हैं। सीनट हितीय सदन है। इसे दीवान ए-नेगर कहत है। इसके 38 सदस्या म से 22 सदस्य राज्य विधान मण्डला द्वारा निर्वाचित हात हं और 16 सदस्या को सच के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। अत मलयशिया की सीनेट आधिक रूप म राज्या का सदन है। मलयशिया का राज्याध्यक्ष राजा होता है। यह 5 वप के लिए मलाया प्रदेश के 9 राजाओ द्वारा अपनी मजलिए म निर्वाचित किया जाता है। मलयशिया म संसदीय शासन-व्यवस्था का अपनाया गया है । राजा सबधानिक अध्यक्ष होता है । प्रधानम त्री वास्तविक कायपालिका है ।

मलयश्चिया म एवल यायपालिका है। सर्वोच्च यायालय इसक शीप पर है। इस सम एव राज्य तथा परस्पर राज्या के मध्य उत्पन्न होन वाले विवादा म

मीलिय क्षेत्राविकार प्राप्त है।

मतवावाया मध म न द्रीय शासन सिद्धा त एव व्यवहार दाना म ही अत्यधिन 'गितशाली है। सपवाद क द्रथ स्वरूप (Dual Federation) न अय म मतविवया अद-मध (Quasi Federation) है। मविषान के अनुच्छेद 76, 94, 150 एव

159 के अन्तगत केन्द्र को राज्यो की स्वायत्तता के अतिक्रमण का अधिकार है। भारत की तरह संघीय ज्ञासन को सकटकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं और बाह्य सकट एव आर्थिक अध्यवस्था की दशा म संघीय सासन राज्या के शासन अपने नियानण म ले सकता है। राज्यों की तुलना में सघ के वित्तीय स्रोत अधिक आय के है। एक्साइज डेयुटी एव आय-कर संघीय क्षेत्राधिकार के अधीन है। राज्या की वित्तीय स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर है। वे सघीय शासन के आर्थिक अनुदाना पर निमर रहते है। केंद्र एवं राज्या के मध्य करों से आय एवं अनुदाना के वितरण हत संघीय वित्तीय आयोग की सर्विधान द्वारा व्यवस्था की गयी है । मलयेशिया मे एक दलीय व्यवस्था है । मलयेशिया के सघ में सिगापुर के शामिल होने का प्रश्न बहुत दिनो तक विचाराधीन बना रहा था । सिंगापुर शामिल भी हुआ पर तु शीघ्र ही पृथक हो गया । इसका कारण जातीयता (Racialism) है । मलयेशिया एक जातीय सथ (Racial Federation) है । मलयेशिया की मूल जाति मलय आर्थिक हिन्द स पिछडी होने के कारण सधीय व्यवस्था के अत्रगत अपने क्षेत्र म अपनी शिक्षित जनता के लिए रोजगार के अधिक अवसरा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहती है। अत संघीय व्यवस्था को कायम रखने के लिए वे प्रयत्नशील एव इच्छक हैं। सिगापुर में चीनी लोगों की जनसरमा अधिक है। सिगापुर के सब म सम्मिलित होने से मलब जाति अल्पसख्या में रह जाती है अत मलयेशिया के सघ म सघव क्षेत्रों के सघ्य न होकर जातियों (races) के मध्य है। क्षेत्रीय मित्रता जातीय विभेद द्वारा आवत है। अंत लामा का बैटवारा जातीयता (races) के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए, 1955 ई मे तक अब्दल रहमान ने अपने प्रथम मित्रमण्डल म 6 मलय. 3 चीती और 1 मारतीय को मन्त्री नियुक्त किया था। किसी को यह चिन्ता नही थी कि म दीगण किस क्षेत्र अथवा राज्य के निवासी है। सभी जातिया इससे स तुष्ट थी कि उनकी जाति को मिनिमण्डल म प्रतिनिधित्व उनको सरया के अनुपात में प्राप्त हुआ है।

मलयशिया के अमुद्र-तट के दूसरे कितारें पर जिटिश बोर्नियों ना क्षेत्र है जिसम सरावक, उत्तरी बोर्नियों एव ब्रूनी के प्रदेश है। मलाया से इनके वहुत कम सम्बंध हैं। ब्रूनी के प्रदेश म मलय जाति के लोग निवास करते हैं।

1963 ई में जात राज्योय समिति की स्थापना उत्तरी वार्तियो एव सरावक को मलयेशिया सप्त म शामिल करने के लिए की गयी थी। समिति ने अपने प्रतिवेदन म यह सिफारिश की थी कि मलयेशिया ने सिवान को इस प्रकार संशोधित किया जाना चाहिए कि उसम नवीन राज्यों की इच्छाओं एव स्थिति की समुचित स्थान प्राप्त हो सर्व । इसके बािरिफ उत्तरी वोनियो एय सरावक का अपना पृथक सिवान मी होना चािहए । सिक्त्या का पुनविभाजन किया जाना चाहिए और बोर्तियों को अप्त राज्यों के भेपेशा बिचक शक्तियों प्राप्त होनी चािहए तथा उसका अधिक विद्याय स्रोती पर नियायण होना चािहए, सचीय शासन को पर्योच्च वित्तीय स्थान करनी चािहए। नवीन विश्वानमण्डल म बाित्यों राज्य के दो निवाचित सी

एव 🖥 अतिरिक्त मनोभीत सीनेटरो को स्थान मिलना चाहिए । वीर्तियो के प्रतिनिधियो को राज्य विधानमण्डल द्वारा चुने जाने की व्यवस्था होनी चाहिए ।

नाइजीरिया

नाइजीरिया पश्चिमी अफ़ीका मे नवोदित स्वतात्र देश है। यह सबस बहा ब्रिटिश उपनिवेश या। 1954 ई के सविधान द्वारा नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना की गयी। नाइजीरिया के अतगत उसके उत्तरी, पूर्वी एव पश्चिमी क्षत्र तथा दक्षिणी कामरून (South Cammeroon) का प्रदेश शामिल है। दक्षिणी काम रून पर 1918 ई मे जमनी का अधिकार या और प्रथम युद्ध के पश्चात इसे यात क्षेत्र (Trusteeship Territory) घोषित कर दिया गया था । 1 अक्टूबर, 1960 र को ब्रिटिश अधीनता से नाइजीरिया स्वतः त्र हुआ और वहाँ वतमान सविधान ला हुआ। नाइजीरिया 3,93,250 वगमील के क्षेत्रफल वाला एक विशाल देश है। इसमे विमिन जातिया एवं कवीले तथा भाषा एवं घम के व्यक्ति रहते हैं। उत्तरी नाइजीरिया म होशा/फुलानी (Hausa|Fulanı) जाति, पूर्वी क्षेत्र में इबी (Ibo) जाति, पश्चिमी क्षेत्र म यूरूव (Yurab) जाति के व्यक्ति निवास करते हैं। इनम गम्मीर सामाजिक, राजनीतिक एव सास्कृतिक मतभेद हैं। पूर्वी एव पहिचमी क्षेत्र मंगर मुसलमान जनसंख्या का बाहुल्य है तो उत्तरी नाइजीरिया में मुसलमान निवास करते हैं। सघीय व्यवस्था के अनुकूल जहा नाइजीरिया मे ये विमक्तकारी तस्व विवामन है वहाँ सम्पूण नाइजीरिया में व्यापार के लिए उपयुक्त सुव्यवस्थित यातायात की सुविधा है। उत्तरी नाइजीरिया के निवासी एकारमक व्यवस्था के विरुद्ध हैं और सर्घ में जनका प्राधाय है। 1954 ई के निर्वाचनों में विजयी उत्तरी जन-काँग्रेस (North Peoples Congress) नामक दल ने के द्वीय शासन को कम शक्तियाँ देने का समयन किया था और वह उसकी स्थिति को एक प्रवाध निकाय (Managing Agency) की तरह कर देने का पक्षपाती था।

नाइजीरिया के सिवधान म दो सूचिया हैं—सघीय सूची एव समवर्ती सूची। सघीय सासन को दोना सूचिया के विषयों पर विधि-निर्माण का अधिकार है। समर्वी सूची के विषय पर ने द्र एव घटक राज्या दोना को ही विधि निर्माण का अधिकार है। समर्वी सूची के विषय पर ने द्र एव घटक राज्या दोना को ही विधि निर्माण का अधिकार है परन्तु दोना म विदाध की दशा म घटका की विधि अवैध होती है। अविध्य रात्तिमा घटक इनाइया ने प्राप्त हैं। सविधान ने सशोधन म के द्र एव राज्य बात में स्थिति अपिकार है। के द्रीय विधानपण्डल नो सकटनासीन शिक्ती प्राप्त हैं। सान्दरान म में द्रीय ससद का सम्पूण देश के लिए गाति क्यवस्था एव सुरासन में हिंदि ने विधि निर्माण का अधिकार है (धारा 65)। अतरराष्ट्रीय सीम्या एव सर्वार्थ ने निर्मा ने मार्थ के विधि निर्माण का अधिकार है। सिरी प्रदा्त में स्था प्रमुख है। सिरी प्रदा्त में सुप्त होने को अधिकार प्राप्त नहीं है। गियाना इरारा प्रदा्त स्वरार्थ पर अपने नामपाल हारा प्रदा्त स्वरार्थ पर अपने नामपाल नामपाल होने स्वरार्थ पर अपने नामपाल नामपाल साम्प्र है हिसी प्राप्त नामपालिया जिल्ला निर्मा स्वरार्थ पर अपने नामपालिया नामपालिया ने हिस स्वरार्थ स्

के उल्लघन की दक्षा मे सघीय ससद द्वारा दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करने पर सम्बिंघत प्रदेश के विषय मे विधि बनाने का अधिकार उसे प्राप्त हो जाता है। बाइफरा ने प्रयक्ता के लिए सशस्त्र विद्रोह किया या जिसे के द्वीय शासन ने सेना का प्रयोग करके दवा दिया।

आर्षिक हिन्द से सभी क्षेत्र परस्पर निभर है। आय के प्रमुख स्रोतो पर के द्वीय सरकार का अधिकार है, जैसे—कम्यनिया पर कर, निर्यात कर आदि के द को प्राप्त है। पर तु के द्वीय सरकार ने स्वेच्छा से निर्यात-कर लगाना छोड़ दिया है। व्यक्तियो पर आय-कर प्रदेशा की सरकारा द्वारा लगाया जाता है। के द्व द्वारा आर्थिक अनुदान दिये जाते हैं। नाइजीरिया मे समय-समय पर वित्तीय स्थित पर विचार करने के लिए वित्त-आयोग (Fiscal Review Commission) की स्थापना होती रही है। रायसमन आयोग (Raisman Commission) के सुकाव पर राष्ट्रीय आर्थिक परिषद (National Economic Council) की स्थापना हुई। यह प्रदेशा के मध्य सहयोगी सस्ता है। वतमान स्थिति मे नाइजीरिया के प्रत्येक प्रदेश को पृथक रूप से आर्थिक निमरता प्राप्त करना कठिन है।

नाइजीरिया के सविधान में के द्रीय शासन को सिद्धा तत श्रक्तिशाली बनाया गया है परंतु व्यवहार म यह कमजोर सिद्ध हुआ। इसका कारण नाइजीरिया में क्षेत्र-

बाद एव जनजातीयवाद (Tribalism) का बाहुल्य एव प्राधान्य है।

सम्बाद की आधुनिक प्रवृक्तियाँ

प्रत्येक सभीय राज्य म घटक इकाइया के मूल्य पर के द्रीय शासन की शक्तिया

म वृद्धि आधुनिक सम्बाद की सर्वाधिक महत्वपूण प्रवृक्ति है। सपुक्त राज्य अमेरिका

म वृद्धि आधुनिक सम्बाद की सर्वाधिक महत्वपूण प्रवृक्ति है। सपुक्त राज्य अमेरिका

म सभीय शक्तिया का विकास समवतीं क्षेत्रशिकार के सिद्धात (Doctrine of Implied Powers) के माध्यम स हुआ है। के द्रीय सरकार की शक्तियों में विकास का अप

प्रो ह्रियिर के अनुसार यह नहीं समक्रता चाहिए कि के द्रीय शासन ने राज्या के क्षेत्रा

विकार का अदिकमण करके भीरे भीरे राज्यों की उन शक्तियों को हिप्या लिया है

जो प्रारम्म राज्या को प्रदान की गयी भी। अ के द्रीय शासन की शक्तियों के

विकास के लिए ह्रियर के अनुसार बार तत्व उत्तरदायों हैं। वे इनमश युद्ध आर्थिक

मन्दी, राज्य द्वारा सामाजिक सवाजा में विकास एवं यातायात और उपोगा में मानिक कार्ति । इसरे राज्यों के, ग्राक्त राजनीति, म दी की राजनीति, कल्याणकारी राजनीति एवं एजिन (यन्त), सपदाद म के द्रीकरण के लिए उत्तरदायों तत्व है। "100 सपीय

¹⁰² Wheare K C Federal Government p 237
Wheare ascribes four factors of the development of the powers of federal governments, they are 'War, economic depressions, the growth of social services and the mechanical revolution in transport and industry To express the same thing in different words they were power politics, depression politics welfare politics and internal combustion engine — Ibid. p 239

राज्यों की काय-पद्धति भी के द्रीकरण में सहायक है। मुद्ध एवं आर्थिक मंदी के वात मे परिस्थितियाँ अधिकाधिक के द्रीय नियात्रण को अनिवाय बना देती हैं और इस प्रकार अस्यायी रूप से के द्रीय शासन की शक्तियों म वृद्धि हो जाती है। लेकिन कल्याणकारी राज्य एव यात्रिक काति वेद्रीय शासन की शक्ति में वृद्धि करने वात स्थायी तत्व हैं। सुहढ वित्तीय स्थिति के कारण के द्रीय सरकारा की शक्ति म विकास स्वाभाविक है। सामाजिक क्ल्याण की योजनाओं के फलस्वरूप राज्यों पर केंद्रीय नियानण में वृद्धि हुई है। स्विटजरलैंण्ड के केण्टना के द्वारा आय-कर सधीय शासन को प्रदान कर दिया गया है। अमेरिकी सविधान के 16वें सत्तोधन द्वारा आय कर सघीय शासन को सौप दिया गया है । आस्ट्रेलिया मे विभिन्न राज्या एव सघीय शास^त की 23 प्रकार की आय पर कर प्रचलित थे। द्वितीय विश्व-पुद्ध की परिस्थितिया है वाध्य होकर राष्ट्रीय सरकार ने राज्यों से आय कर का के द्रीय शासन के पक्ष न स्याग दने का प्रस्ताव किया । पर तु राज्य इसके लिए सहमत नहीं हुए । के द्वीय सर कार ने इस पर अनेक विधिया पाण्ति की जिससे आय कर लगाने की अधिकार उसे प्राप्त हो गये और राज्यों को मुआवजे के रूप में अनुदान देना स्वीकार किया। कनाडा के प्राता ने द्वितीय विक्व युद्ध से उत्पत्र परिस्थितियों से बाध्य होकर युद्ध-कार्त के लिए 'आय कर' एव 'निगम कर' के द्वीय शासन को सौपना स्वीकार किया था। डोमीनियन सरकार ने क्षतिपूर्ति के रूप मे प्रात्तो को अनुदान प्रदान किया। 1947 ई में ओ टोरियो एव क्यूबेक प्रातों को छोडकर अय प्रातों ने इस विषय पर मिर्क्य के लिए समसीते किये। 1952 ई मं औटोरियो मी इस व्यवस्था में शामिल है। गया । अब प्रति पाच वप के पश्चात नवीन समभौते कर लिये जाते हैं।

प्रा ह्वीयरे के अनुसार "युद्ध एव आर्थिक मन्दी का बार-बार होना संपीय द्यासन के लिए हितकर नही है। उन्न इसम स देह है कि आस्ट्रेलिया की संपीय व्यवस्था मिक्य में किसी युद्ध या आर्थिक म दी के दुष्परिणामों को बर्दार्थ कर सकेगी। शान्ति एव सम्पन्नता न कि युद्ध एव आर्थिक म दी, संपीय धासन की सफलता के लिए आवश्यक खतें हैं।"108

के त्रीकरण की प्रवित्त के साथ संधीय अ्यवस्था के अन्तवात राज्या या घटक इकाइयी में स्थानीयता की प्रवृत्ति का जी विकास हुआ है। साया, क्षेत्रीयता एवं सास्य तिक निष्ठा ने के द्रीकरण विरोधी मायनाओं को विकसित किया है। ह्रीयर के अनुसार सभी सथा की इकाइया द्वारा अब अनेक कार्यों को सम्पादित किया जाता है जा संधीय व्यवस्था के जम के समय उनके द्वारा सम्पादित नहीं किये जाते थे। उदी इरण के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक संवाएँ एवं ही विषय है। इन सेवाओं के सेवान के सिस्तार के साथनाथ पाण्या द्वारा इन पर पहले से कई पूना अधिक धन व्यव किया जाता है। स्थानीयता की भावना न राज्यों में आहमचेतना एवं द्वारा की

¹⁰⁴ Wheare K C op at, pp 103 106 105 Ibid, p 239

जम दिया है और के द्वीय शासन की शक्ति के विकास के अनुपात मंही राज्यों मे आत्मचेतना एव हढता बढती गयी है। यह कहना अधिक ठीक होगा कि राज्या म स्थानीय निष्ठा के दीकरण में बद्धि के अनुपात म विकसित हुई है। के दीकरण के फल-स्वरूप राज्यों ने यह अनुभव करना प्रारम्भ कर दिया है कि जनकी स्थिति को खतरा है और वे इसकी कड़े शब्दा म शिकायत करते हैं। कभी कभी तो केंद्र के अयाय के कारण वे सघ से पथक होने की चर्चा तक करने लगते है। पश्चिमी आस्ट्रेलिया ने आस्ट्रेलियाई सघ से पृथक होन के लिए हिसारमक आ दोलन तक प्रारम्भ कर दिया था। कनाडा के क्युवेक एवं ओ टोरियो राज्यों की सरकारे तथा आस्टेलिया के तस्मा-निया एव दक्षिणी आस्ट्रेलिया नामक राज्यों ने के द्रीय शासन के निरन्तर हस्तक्षेप का दृदतापुर्वक विरोध किया है। केन्द्रीय शासन की शक्ति में विद्व से आतिकत होकर एक गुट बनाकर राज्यो द्वारा अपने अधिकारो की रक्षा के लिए प्राणपण से प्रयत्न किया जाता है। इससे पृथकता की मावना को बल मिलता है। भारतीय सब म तमिल-नाडु की द्रविड मुस्नेत्र कडचम (DMK) की सरकार अधिकाधिक स्वतन्त्रता की माग कर रही है। 1969 ई म चतुथ निर्वाचन के बाद मारत मे गैर-काग्रेसी सरकारो ने केंद्र के विरुद्ध मिलकर राज्या के अधिकारों की रक्षाय एक सम्मेलन बुलाया था और एक जुट होने का प्रयत्न किया था। सघीय राज्यों में जहां के दीकरण वढ रहा है वहां के द्र एव राज्यों में परस्पर निभरता एवं सहयोग का भी विकास हुआ है। प्रत्येक सघ में अनेक सहयोगी सस्याएँ विकसित हुई हैं। द्वध सचवाद का स्थान सहयोगी सघवाद ने ले लिया है।

अत के द्रीकरण एव पृथकताबाद (Centralism and Separatism) आयु-निक समबाद की वो अनिवाय सलग्न (twin) विद्योपताए है। इनम के द्रीकरण की प्रवित्त अधिक मुखर है। के द्रीकरण की बढती हुई प्रवित्त के मध्य पृथकताबाद की उपस्पिति ने समबाद को एक व्यावहारिक एव वास्तविक तथ्य बना विया है।

व्यवस्थापिका¹ LEGISLATURES

लोकता नीय देशों में शासन के तीन अगा म से व्यवस्थापिका का सबसे महत्व पूण स्थान है। इसमें जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। इनके द्वारा देश के विष् विधि का निर्माण किया जाता है। विधि शासन का आधार है अत राज्य मध्यस्था पिका की स्थिति के द्वीय होती है। विधि के द्वारा ही व्यक्ति के अधिकारों की सां की जाती है। आ तरिक शांति एव सुरक्षा की व्यवस्था तथा याय का प्रशासन किया जाता है। विधि के आधार पर ही राज्य के विधिन विधिन विधिन से सित्ता प्राप्त करते हैं और उसका प्रयोग करते है। व्यवस्थापिका लोकत त्रीय देशों में भागिंवह "यास" (brant trust) वी भूभिका निभागता है।

क्यवस्थापिकाओं को विभिन्न देशों म भिन-मिन नामों से वुकारा जाता है जसे—ससद (Parliaments), कायेस (Congress), एव सामान्य समाएँ (General Assemblies) । ससद के अग्रेजी पर्यायवाची शब्द पालियामेण्ट (Parliament) को थाते हैं 'वार्तों का स्थान' । ससद के आलोचकों ने व्यवस्थापिकाओं को 'वार्ता की कुकाना' (Talking Shops) की सक्षा दी है । इयक्त प्रवस्थापिका को ससद (Parliament) की सज्ञा दी गयी है । सयुक्त राज्य अपरिका में समीय व्यवस्थापिका को ससद (Parliament) की सज्ञा दी गयी है । सयुक्त राज्य अपरिका में समीय व्यवस्थापिका को काग्रेस (Congress) एव फास म राष्ट्रीय समा (National Assembly) की सन्ता दी गयी है । सोवियत रूप म के द्रीय व्यवस्थापिका को 'सुप्रीम सावियत' (Supreme Soviet) कहा जाता है । जापान में आईट (Diet) तथा स्विट्जरत्वाड में फेडरल असेस्वार्ती (Federal Assembly) चुकारा जाता है । अभुक्त राज्य अमेरिका को इंग स्था—राज्या—में व्यवस्थापिका (legislature) अब्द का प्रयोग किया गया है । अमेरिका को स्थान प्रथम में ब्यवस्थापिका (Legislature), उन्तीत म जनरल असंस्थली (General Assembly), तीन राज्यों म केजिस्सेटिंग असम्बर्ती म जनरल असंस्थली (General Assembly), तीन राज्यों म केजिस्सेटिंग असम्बर्ती

विधानाग, विधानमण्डल, विधानपालिका, विधायिका, व्यवस्यापिका द्वारात के विधि निर्माण करने वाले अब के लिए प्रयुक्त हि दी मापा के पर्यायवाची दाव्य हैं।

(Legislative Assembly) एव वो राज्या में जनरल कोट (General Court) कहा जाता है 1° व्यवस्थापिका एकसदनीय अथवा द्विसदनीय होती है । इगलैण्ड, अमे- रिका, फान्स, मारत, शोवियत रूस, स्विट्जरलैण्ड, पिश्मी जमनी, कताडा आस्ट्रेलिया आदि देशा की व्यवस्थापिकाएँ द्विसदनारमक हैं । दोनो सदनो के नाम हर देश में निज्ञ मित्र है । इगलैण्ड में निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स (House of Commons) एव उज्ज सदन को लॉड समा (House of Lords), समुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिनिधि समा (House of Representative—निम्न सदन) एव सीनेट (Senate—उज्ज सदन), स्विट्जरलैण्ड में राष्ट्रीय परिषद (National Council—निम्न सदन) एव राज्य परिषद (Council of States—उज्ज सदन), सारत में लोकसमा (Loka Sabha or the House of Peoples—निम्न सदन), एव राज्य सा (Rajya Sabha or the Council of States—उज्ज सदन), सोवियत रूस म निम्म सदन को सब सीवियत (Soviet of the Union) एव उज्ज सदन से से सिव्यत रूस

व्यवस्थापिकाओं का विकास

विधि-निर्माण आधुनिक राज्यों का प्रमुख काय है। प्राचीन काल में विधि-निर्माण न तो घासन का प्रधान काय एव दायित्व ही या और न वतमान काल की भाति प्रतिनिधि समाओ द्वारा विधियों का निर्माण ही होता था, अपितु विधिया दीध-कालीन परम्पराओं एव रीति-रिवाजो पर आधारित होती थी। समय बीतन के साय-साय इन सामाजिक विधियों का महत्व कम होता चला गया और व्यवस्या तथा धारित की स्थापना के लिए कायपालिका द्वारा विये जाने वाले आदेश विधि का रूप धारण करने लगे।

प्रतिनिधि प्रणाली के उदय के सम्ब म गेटेल के अनुसार पर्याप्त मतभेद हैं। परम्परागत मत यह है कि प्रतिनिधि समानों का विकास उत्तरी यूरोप के देशों में प्राचीन स्प्राची। (Teutonic Folkmoots or Assembles of Freemen) से हुआ है। 'इन समाओं में जल जाति के प्रमुख सामिल होते थे। यह समाए परामदावार्य ही परिषद के रूप में काम करती थी। और सामाय नीति से सम्बचित महत्वपूण प्रश्मों को निश्चित करती थी। इंगलण्ड में इस प्रकार की समा का प्रारम्भिक रूप Witenagemot—विद्यालयों की समा—थी। समाज के प्रमुख व्यक्ति इसम माग लेते थे। दलका सम्मेजल वप मं कई बार इंगलण्ड के राजा के द्वारा जुलाया जाता था। धीरे-धीर यही सस्या राज्य की प्रमुख सस्या महा परिषद (The Great Council of the Kingdom) बन गयी। नवीन कर लगाने के लिए इसकी स्वीकृति आवस्यम

Wheare, K C Legislatures p 1

³ Gettell, R G Political Science, pp 309 10

थी । यही सस्या कालात्तर मे त्रिटेन की प्रतिनिधिस्वपूण राष्ट्रीय व्यवस्यापिश के रूप म विकसित हो गयी ।

ब्रिटिश ससद वतमान ससदो को जननी मानी जाती है। ब्रिटिश ससद से हैं प्रतिनिधि शासन की धारणा एव ससदीय शासन प्रणाली के विचार का प्रादुर्माव एवं विकास हुआ है। अत ब्रिटिश ससद का इतिहास 'व्यवस्थापिका' या 'विधानमध्यं का इतिहास माना जाना चाहिए। व्यवस्थापिका से सम्बध्धित अनेक रिद्धाता हो नीव ब्रिटिश ससद के विकासकाल म पडी है और इन्हीं सिद्धातों को लोक्त ती की लोक्त के ब्रिटिश सद के विकासकाल म पडी है और इन्हीं सिद्धातों को लोक्त के क्षान वी का की लोक्त है। ब्रिटिश सद के विकास का विकास के विवास के विवास के विवास की विवास की

उपर्युक्त उल्लिखित ब्रिटिश राज्य की महा परिपद (Great Council of the Kingdom) मे काला तर म समाज के नवीन वर्गों को भी प्रतिनिधित दिया गया । फलस्वरूप उसके आकार मे वृद्धि हुई और सदस्या को श्रेणियों में वर्गीहर्त किया गया। 1215 ई इसके महान् घोषणापत्र-मगना कार्टा-का वय है। द्वारा लोकत नीय निय नण की नीव का शिला यास नही हुआ था अपितु यह तो केवल राज्य की शक्तिया को सामन्तो द्वारा सीमित करने कात्रयत्न था। इगलण्ड के राजा की जब धन की आवश्यकता होती थी तब वह छोटे भू स्वामियो से सम्पक स्यापित करता था। छोटे भूमिघर बहुसस्या मे वे और वे धन प्रदान करने की क्षमता रहते थे। ब्रिटिश राजाओ द्वारा इन छोटे भूमिधरा को अपने कुछ प्रतिनिधि नामाकित करो के आदेश दिये जाते थे जिससे वह उनसे कर सम्बाधी स्वीकृति प्राप्त कर सके। राजी द्वारा बेरन (Baron), पादरी (Clergy), नाइट (Knight) एवं वर्गेस (Burgess) आदि जिनम कर देने की क्षमता थी, आमितित किये जाते थे। 1265 ई तक इस प्रकार गठित ससद शासन का एक स्थायी अग वन चुकी थी। प्रारम्भ म ससद की सदस्यता सम्मान या सत्ता का स्रोत नहीं मानी जाती थी अपितु राजाना एवं इन्ड मय के कारण अनिच्छापूरक ही इसकी सदस्यता ग्रहण की जाती थी। इन प्रारम्बिक ससदो से यह अपेक्षित या कि वे राजा की बातो को सुनकर ही उन्हें स्वीकृति दे। इन ससदा का उद्देश्य लोकतात्र की स्थापना करना नहीं था अपित शाही राजस्य में वि करताथा।

प्रारम्भ मे सबद के अधिवेशन एक निकाय के रूप म ही होते थे। परन्तु बार म ससद समाज के तीन वर्षों—साम त, पादरी एव सामा य प्रजाजनी (commons)— का प्रतिनिधित्त करने वाले तीन सदना में विभाजित हो गयी थी। 1295 ई म उच्च पादित्यी एव साम तो के हितो म समानता होने के कारण वे एक सदन—लॉड समा— म सगठित हो गये। छोटे साम त एव स्वत त्र प्रमिश्चर हित समान होने वे कारण एक साथ मिल यथ और एक सदन—कॉमन्स समा—म सगठित हो गये। अत विटेन म

⁴ Gettell R G op cat, p 310

द्विसदनीय प्रणाली का निर्माण सुनिश्चित योजना का परिणाम नही था अपितु आर्थिक एव सामाजिक परिस्थितियो का परिणाम था। कॉम स समा के सदस्य प्रतिनिधियो के रूप म माग लेते थे फलत इससे वतमान क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धात की नीव पड़ी। लॉड समा के सदस्य वर्गीय प्रतिनिधित्व के सिद्धात के अनुसार व्यक्तिगत रूप से ही लॉड समा में माग लेने के लिए आमित्रित किये जाते थे। लॉड समा मायाय म महापरियद (Great Council or Magnum Councillum) का स्थामीकरण था।

मूरीप के अय देशों में इगलण्ड की अपंक्षा ससदा—प्रतिनिधि सदनो—का विकास भीमी गति एव मिन्न तरीके से हुआ है। जमनी, फ़ास एव स्पन में मध्ययुगीन प्रतिनिधित समाएँ थी। नगरा के विकास एव राष्ट्रीय ससदों म उनके द्वारा प्रतिनिधित की सारण के विकास एव राष्ट्रीय ससदों म उनके द्वारा प्रतिनिधित की सारण के विकास म महत्वपूण योग है। गेटेल की सारण का प्रतिनिधित की प्राप्त सदना में प्रतिनिधियों को पृथक स्पत्त की सार विकास गा विष्क प्रयक्त सदना में मतदान करते थे। इन देशा की ससदों में तीन एव कमी-कमी पार सदन होते थे। इर वग अपने अधिकारा एवं हिता की रक्षा के लिए सजन एवं प्रयक्तियों ले हिता था। प्रतिनिधि जिस वग द्वारा निर्वाचित किय जाते थं, उसके हिता की रक्षाय नियुक्त अभिकर्ता जैसी स्थित रखते थे। यह विचार अभी तक विकासित नहीं हुआ था कि प्रतिनिधि सम्पूण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। फ़ास जसे देश म इन मध्यपुतीन समाओं का कई शतिबिधी तक अधिवेशन न बुलान के कारण कोई अस्तित्व ही नहीं रहा था। वा प्रतिनिधित्व की धारणा का अत कि इसी की समय हुआ और तभी राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व की धारणा का अत कि इसी ती समय हुआ और तभी राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व की धारणा की स्थापना हुई थी। 19वी सताबी में पूराप में आधुनिक अर्थों म राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व पुक्त ध्यवस्था पिकाओं की स्थापना हुई थी। 1"

व्यवस्थापिका के प्रकार

व्यवस्थापिका के दो ही मुख्य प्रकार हं एकसदनीय (Unicameral legislature), एव द्विसदनीय व्यवस्थापिका (Bicameral legislature) । एकसदनीय व्यवस्थापिका की अपक्षा द्विसदनीय व्यवस्थापिका का ही अधिक प्राधा य है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त वर्गीकरण के तीन अय आधार भी हो सकते है (1)

सस्या, (II) रचना की पद्धति, और (III) अधिकार एव शक्तिया।

(1) सदस्य सरया की दृष्टि से कुछ व्यवस्थापिकाएँ लघु या कम सदस्य-सस्या वाली हैं, तो कुछ वृहद या बहुसदस्यीय है, जसे---निटिश लॉडसमा एव रूस की सुप्रीम सावियत। वरन्तु यह वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं है। जनेक छोटे देशों म अपक्षाकृत वहद व्यवस्थापिका पायी जाती है, यथा---इमलैण्ड। इसके विपरीत, वड देश मारत की सदस्य सस्या निटिश ससद की सदस्य सस्या सं काफी कम है।

⁵ Gettell, R G op att, pp 311-12

देखिए अध्याम 9 द्विसदनवाद ।

(2) रचना की दृष्टि से व्यवस्थापिकाओं के दो वग है (1) निर्वाचित (Elected), एव (11) अनिवांचित (Non-elected) । (1) निवाचित व्यवस्थापिकाओं म प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित सदना के उदाहरण हैं इंगलण्ड की काम स समा, अमेरिकी प्रतिनिधि सदन, सुप्रीम सोवियत का निम्न सदन सघीय सावियत (Sovict of the Union) स्विटजरलण्ड की संघीय समा का निम्न सदन राष्ट्रीय परिषद (National Council) एव भारतीय संसद का निम्न सदन लोक समा। अप्रत्यक्ष रीति से निर्वा चित सदना के उदाहरण है 1913 ई तक अमरिकी सीनेट, मारत की राज्यसमा एव अनेक मारतीय राज्या (Indian States) की व्यवस्थापिका के उच्च सदन विधान परिपद (Legislative Council)। मारत की ससद का उच्च सदन-राज्यसमा-आशिक रूप से निर्वाचित है, इसके 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। दक्षिणी अफीका की सीनेट के 8 सदस्य राज्याध्यक्ष द्वारा मनोनीत किंग जाते है। लका के प्रथम सविधान के अतगत निर्मित सीनेट आशिक रूप में निर्वाचित एव मनोनीत सदन थी। (11) अनिर्वाचित (Non elected) ब्यवस्थापिकाओ के अ तगत वशानुगत एव मनानीत व्यवस्थापिकाएँ आती हैं। लॉड समा ऐसा हा एक सदन है। उसके सदस्य वशानुगत एव मनोनीत होते है। कनाडा की सीनट के सदस्य गवनर जनरल द्वारा जीवन भर के लिए मनोनीत किये जाते हैं। वर्मा के प्रयम सनिधान के अतगत हितीय सदन-Chamber of Nationalities-म 125 सदस्य थे जो विभिन्न राष्ट्रीयताओं (nationalities) द्वारा चुने जात हैं। शान एवं करन राज्यों के प्रतिनिधि वहां के प्रमुखा द्वारा निर्वाचित किय जाते थे अत वर्म का उच्च सदन अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित सदन था।

(3) अधिकार एव शक्तियों को बद्धि से व्यवस्थापिकाओं को पूण प्रमूल सम्पन्न एवं आधिक प्रमूख सम्पन्न वर्गों में बाँट सकते हैं । ब्रिटिश समद प्रण प्रमूख सम्पन्न व्यवस्थापिका का उदाहरण है। मारतीय समद और अमेरिकी कायर ब्रिटिश ससद की प्राप्त प्रमूख सम्पन्न नहीं हैं। जिलित सचिधान, मीतिक अधि कारों के उत्लेख एवं शक्तियों के विमाजन से समद की प्रमूख-सम्पन्नता पर सीमा नियारित हो आती है। व्यवस्थापिकाओं के निम्म सदन उच्च सदन की जरेक्षा अधिक रात्तियाली होते हैं। व्यवस्थापिकाओं के निम्म सदन उच्च सदन की जरेक्षा अधिक रात्तियाली होते हैं। व्यवस्थापिकाओं के निम्म सदन उच्च सदन की जरेक्षा अधिक रात्तियाली होते हैं। व्यवस्थापिकाओं के निम्म सदन उच्च सदन की जरेक्षा अधिक रात्त्वियाली होते हैं। व्यवस्थापिकाओं कर स्वत्वस्थाल है।

उपयुक्त वीनो वर्गोक्षण एक दूसरे का अविक्रमण करते हैं। जैस-अमिकी सीनट लघु होते हुए मी एक शक्तिशाली सदन है और उच्च सदन होते हुए मा बहु निर्माचित सदन है। इसके विषरीत लॉड समा बहुद् एव बशानुसत है परन्तु प्रक्तिशैन सदन है। ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये जा मकते हैं। इस प्रकार के अविक्रमण से बर्माकरण की बज्ञानिकता समाप्त हो जाती है। अत एकसदनीय एव द्विसदनीय वर्गी करण हो अधिक प्राप्त है।

एक लम्बं समय तक द्विसदनीय व्यवस्थापिका राजनीति विनात का स्वी^{कृत} निद्धात रही है। फलस्वरूप विश्व की अधिकादा व्यवस्थापिकाएँ द्विसदनात्म^{क हैं}। ग्राइस का मत है कि यह सिद्धान्त अमेरिकी गर्वैधानिक सिद्धाता का बाधार है। सर हेनरी मेन एव बेजहोट न भी द्वितीय सदना का समयन किया है । 18वी एव 19वी सदी के प्रारम्भिक काल म एकसदनीय व्यवस्थापिका के प्रति अधिक मुकाव पा। अमरिकी विचारक वेजामिन फॅकलिन एकसदनीय व्यवस्था का उग्र समयक था। उसन द्विसदनीय व्यवस्था की तुलना एक ऐसी गाडी से की है जिसके दोनो तरफ के दो घोडे विपरीत दिशा म गाडी को खीचते हैं। फलस्वरूप पेन्सलवेनिया राज्य के प्रयम सविधान द्वारा एकसदनीय व्यवस्थापिका का निर्माण किया गया था। इसी समय इगलण्ड के विचारक ये यम न एकसदनीय ससद का सुभाव दिया था। का तिकालीन फास मे एर मदनीय व्यवस्थापिका का विचार अधिक प्रचलित था । इस समय टारगोट (Turgot) एकसदनवाद का प्रवल समयक था। फलस्वरूप 1791 ई के सविधान म सवसम्मति से एक सदन---राष्ट्रीय समा---के निर्माण का प्रस्ताव स्वी-कार किया गया था। 1793 ई के सविधान मे भी एकसदनीय व्यवस्थापिका की ही स्थापना की गयी थी। परन्तु 1795 ई में फास म द्विसदनीय व्यवस्था की अपनाया गया। यह व्यवस्था 1848 ई तक कायम रही। इसी वय पुन अल्पकाल के लिए फास म एक्सदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गयी। 1848 ई म फान्स मे एक-सदनीय व्यवस्था का प्रवल समयक लामाटीन (Lamartine) था। 1795 ई मे हिसदनबाद के समयक Boissy d' Anglas का मत या कि का स की नान्ति के पदचात अनेक बुराइया एव क्टा का कारण एक्सदनीय व्यवस्थापिका के हिमात्मक एव अति-वादी काम हु। एक्सदनीय समाओ की काय-पद्धति म निष्कृष्ट प्रकार की हिंसा, अस्थिरता पित्व एव अतिवादिता का प्राथा य था। केवल कुछ देशा को छोडकर अधिकाश में एक-सदनीम प्रधान देशा न काला तर मे द्विसदनीय व्यवस्थापिका को स्वीकार कर लिया है। इगलण्ड म कॉमनवेल्य-काल (1649-1660) म एकसदनीय व्यवस्थापिका की स्यापना की गयी थी। पर तु राजतन्त्र के पुनर्स्यापन (Restoration of 1660) के पश्चात लॉडसमा की पुन स्थापना की गयी। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम सर्वि-धान (Articles of Confederation) के अत्तयत गठित राष्ट्रीय काग्रेस (National Congress) एकसदनीय व्यवस्थापिका थी । इस व्यवस्था से समी अस तुष्ट थे । फिलाडेलफिया सम्मलन मे संयुक्त राज्य जमेरिका के वतमान संविधान के निर्मानाओ में नवल वेंजामिन फ्रेंकलिन को छोडकर सभी सदस्य एकमदनीय व्यवस्थापिका

के विरोधी थे। इस सम्बाध म हेमिल्टन के निम्न विचार महत्वपूण है द्वीपीय नाग्रेस एकसदनीय सभा के दोषा को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है। प्राय यह हुआ है कि अनक प्रस्ताव उसके द्वारा इसर दिन अस्वीकृत करन के लिए ही पारित

किय गये थे।" केन्ट ने इस सम्बाध में पैन्सलवेनिया एवं जाजिया राज्य के उदाहरण 7 'The proceedings of the single chamber legislative assemblies were marked with violence instability and excesses of the worst kind -Garner op sit, p 548 8 Hamilton Federalist, Nos 62 and 63

देते हुए लिखा है कि इन राज्या में अस्थिरता के फलस्वरूप आवृक्त एवं निर्दानने प्रकार की विधियों पारित की गयी थी। गानर ना कथन है कि स्पन, पुतगाल, नप्ल, में पिसको, दोलाविया, इक्वेडर एवं पीरू आदि सभी राज्या ने एक्सदनीय व्यवस्थापिन का परित्याग कर दिया है और द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की है। परंदु 1931 ई के स्पेन के सविधान के अन्तगत एकसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थित स्थापना स्थापन

मारत के नवीन सविधान में द्विसदनीय व्यवस्थापिका स्थापित की गयी है। कुछ मारतीय राज्या म एकसदनीय व्यवस्थापिका भी है। मध्य प्रदेश म द्वितीय सदर की स्थापना का प्रस्ताव 1959 ई म पारित हुआ या पर तु 1969 ई म ही द्वितीय सदन—विधान परिपद (Legislative Council)—की स्थापना हुई। कुछ मारतीय राज्यों ने द्वितीय सदन को समाप्त करन की माँग की है। साम्यवादी चान म एकतर नीय व्यवस्थापिका है।

व्यवस्थापिका के कार्य

स्थवस्थापिका का प्रधान काय विधि निर्माण करना है। विधि निर्माण के अति रिक्त उसके अ य काय भी है। किसी देश की स्थवस्थापिका के काय उस देश के शि धान के स्वरूप पर निभर करते हैं। स्थवस्थापिका के कार्या एव दायित्वा का विश्वाणी, सबैधानिक कायधानिका तथा प्रशासनिक, याधिक एव वित्तीय श्रेणिया मे वर्गीकृतं क्या जाता है।

1 विधायी एव सवधानिक काय

(Legislative and Constitutional Functions)

परिवतमधील वतमान सामाजिक परिस्थितिया मे प्रति वप प्रत्येक देश म नवीर विभियों की आवश्यकता पढ़ती है। व्यवस्थापिका इस आवश्यकता की पूर्ति करती है। वह विधि निर्माण का प्रमुख एव प्रधान स्रोत ह पर तु एक्सान स्रोत नहीं है। आई निक स्वयस्थापिका। पर इतना अधिक कार भार होता है कि वे अपने इस प्रमुख दायिक को सली प्रकार सम्पादित नहीं कर पाती हैं। इसके अतिरक्त, अनक एंदे विषय होते हैं जिनके सम्बच्ध म विधि निर्माण हुतु विधेष ज्ञान एव योगयता की आव श्यकता होती है। अत व्यवस्थापिका कायपालिका का विधि शताकर उसकी सीमा के अवगत साथ अध्यस्थापिका आदि वनाने ना अधिकार प्रशान कर देती है। इर्द प्रशास वायवस्थापिका आदि वनाने ना अधिकार प्रशान कर देती है। इर्द प्रशास विधान की आपूर्तिक कात में अपनाथार पा व्यवस्थापिका विभाग के प्रशास प्रशास की आपूर्तिक कात में अपनाथारण वृद्धि हुई है। ऐसी विधिया के सत्यम म कमी की लोड़ मामतो स्वस्थ की स्थीकृति की सी आयवस्थवा नहीं पड़ती। वि

सभी देशा की व्यवस्थापिकांवा की विधि निर्माण सम्बन्धी शक्तियाँ समान नहीं

⁹ प्रदत्त विधान के लिए देखिए अध्याय 14 ।

हैं। जिन देशा म व्यवस्थापिकाएँ प्रमुख-सम्मम होती है वहाँ वे हर प्रकार की विधि है। अभा प्रधान प्रभावनामा क्ष्मित्व के सिंद । विदेश सिंद मुहत्व सिंद मुहत्व विदेश सिंद मुहत्व सिंद मु ï का गणाण कर पक्षा हा चया अदाबटन का प्रपत्न । गांच्या प्रपत्न व सुप्त सम्पन्न हैं अंत विधि निर्माण ने क्षेत्र म जस पर किसी प्रकार ना कोई प्रतिन प ^{व्यवस्}यापिका | 229 वर्षेत्र १ वर्षा भाग भागाच्या वर्षा वर्षा वर्षा अभार पा भार आपण प नहीं है। उसके द्वारा निर्मित प्रत्यके विधि देश के यायाव्या के लिए वधनकारी है। ेश है। ज्यान क्षारा मामल अन्यम भाग प्रमु कावालवा कालर व वर्तकारा है। इसके विषरीत, लिखित सर्विधान एवं संघीम देखा म विधानमण्डल संसूत्र प्रमुख-सम्पन्न नहीं होते हैं। फलस्वरूप जनको विधि निर्माण की सक्ति सीमित होती है तथा पालक गहा हात ह। भन्नत्वरूप जगका प्याच गम्भाण का थाक व्यामव हावा ह वया यावालया के डारा विधिया को अवैधानिक घोषित किया जा मकता है। उदाहरणाय भागतवा क डारा व्यववा का वववातक वावित कथा वा भकता ह । उदाहरणाय समुक्त राज्य अमेरिका की काँग्रेस और मारत, कनाडा एवं आस्ट्रेलिया की समदे तथा पद्मा राज्य जनारका का काम्रत जार नारत, कनावा एवं जार्ड्स्पमा का क्षप प्रथा स्विटजरसम्बद्ध की फेडरल असम्बसी की विषयी बक्ति सीमित है। स्विस सविधान म प्रमता को जनमत-सम्रह (Referendum) के माध्यम से एंडरल असम्बेली द्वारा निर्मित जाता का जनभव-तथह (Actividum) क नाब्जन च ४००० व्यवस्था धारा गामव विधिया को अत्वीकृत करन क अधिकार के साथ उपत्रम (Initiative) के माध्यम त्राच्या भा जल्याञ्चल करन का आध्यकार भा ताच अननम (mindasve) मा माज्यम से नदीन विधिया की प्रस्तावित करने का भी अधिकार प्राप्त है। तथातक राज्या मे व त्यान व्यवस्य का अस्तावित करन का वा जावकार आज है। तवास्तक राज्यान सर्विपान की स्थाल्या एवं स्थवस्यापिका की विधियों की वैधानिकता की जाव का भागभा का ब्याव्या एवं ब्यवस्थापका का ग्राथायया का वयातकता का जाय का विकित्तर यायमितिका को प्राप्त होता है। विकित्त स्विट्यरसण्ड म संघीय असम्बन्ती नावार अवस्थातक। का आप्त हाम ह । वाक्य प्रवच्यातक व वाच्य व्यवस्थातिक। की सिंघात की ब्यांच्या का अधिकार प्रदान किया गया है । सामा यत स्थवस्थातिका की विधि निर्माण की शक्ति पर निस्त्रनिश्चित सीमाएँ होती हैं

- (1) सधीय सिवधाना म के द्वीय या सधीय एव घटक इकाइयो की सरकारा म शक्तिम का स्पष्ट विमाजन होता है। समीय एवं भीतीय संस्कार केवल अपने अपने क्षेत्र म सम्बन्धित विषया पर ही विधि निर्माण कर सकती है।
- (2) कुछ देखा म हानीय या या तीय व्यवस्थापिकाओं की शक्ति सीमित होती है लेकिन के डीय व्यवस्थापिका की शक्ति सीमित नहीं होती। जवहरण के लिए, विदेन के अभीन उत्तरी आयरसेण्ड की व्यवस्थापिका की शक्ति सीमित है। दक्षिणी प्रत्य भ व्याम जारा आवरतण्ड भा व्यवस्थापमा भा थाम प्राप्त ए । याचा अफ्रीका की संसद की शक्तियाँ असीमित हैं जबकि उसी गणराज्य के चार प्राची— भणामा पा तत्तव का शाक्तमा असामत ह जवाक जवा गणाराज्य प्राप्त प्राप्त के देव प्राप्त ते तहाल, ओरल की स्टट एवं ट्रासवाल—की ब्यवस्थापिकाओं की शक्तियाँ सीमित हैं।
- (3) एकत भीय राज्या म पांचने फल गणराज्य की भांति यह सम्मन है कि के त्रीय एवं के नीय राज्या म वाचव कव वावराज्य का वाता वर प्रकार र विकास संस्था (व्यवस्थापिकावा म नहीं) म विधि निर्माण की शक्ति प्रभाष ५व छनाय सरकारा (व्यवस्थापकावा भ गहा) भ ग्याय गणनाच का स्वरत विमाजित हो तथा कुछ विषया म प्रतिनिधि समा को विधि निर्माण का व्यवकार हो एवं शुप्र मामलो म कायपातिका की विधि निर्माण का अधिकार हो। पावने फेन भग राज्य में भावपालका का वाम लगाण का जावण र हा। भावज के सिवधान में कुछ विषय पूज्यमा संसद के कीवा तमत है जसे विस्त त्र तावधान म कुछ भवषध पूर्णवया एवद क वाना प्रणव ६ अव प्रथम, इरका, तम्मति एव नागरिक अधिकार राष्ट्रीयवा आदि । उप मामलो म कायपालिका का अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है।
- (4) कुछ देशो की व्यवस्थापिकावा को सविधान द्वारा कुछ विषया म विधि निमाण के अधिकार प्रदान नहीं निया गया है। उदाहरण के लिए, संयुक्त रीज्य अमेरिका की संधीय अपना राज्या की व्यवस्थापिकांका की निय-भेद के आधार पर

नागरिक अधिकारा को सीमित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त, सपुक्त राज्य अमिरका की काग्रेस या किसी राज्य की व्यवस्थापिका के द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति, जीवन व स्वतन्त्रता से विधि की उचित प्रक्रिया (due process of law) के विना वचित नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति की सम्पत्ति विना भुआवना दिय सासन द्वारा हस्तगत नहीं की जा सकती। किसी राज्य को सीनट में समान प्रतिनिधित्व से ससदीय विशि अथवा सवैधानिक सदोधन द्वारा वचित नहीं किया सकता। विधायी शक्ति पर इस प्रकार के प्रतिवच्च मारत, मनवेशिया जैस देशा के नवीन सविधाना से भी हैं।

(5) सवैधानिक सज्ञोधन सम्बाधी विधियो पर व्यवस्थापिका का सामान्यत अनियानित क्षेत्राधिकार नहीं होता । यह व्यवस्थापिकाओ की स्वामाविक विधायी ग्रांति पर प्रतिवाध है । इसलैण्ड एव पूजीलैण्ड की ससदे इसका अपवाद हैं । द्वीयरे का मत है कि "सविधान का उद्देश्य (व्यवस्थापिका सहित) झासन-प्रणाली की स्थापना एवं उसकी व्यवस्था करना होता है । अत यह सवया उचित है कि व्यवस्थापिका को उर्व अम से उच्च नहीं बनाया जाना चाहिए जिसके द्वारा व्यवस्थापिका का निर्माण हुआ है। अ

विधि निर्माण से सम्बाधित एक इसरा प्रकन भी है। व्यवस्थापिकांना हार्य पारित की जान वाली विधिया के सम्बाध म व्यावहारिक दृष्टि से आखिरी तिण्य कीन करता है ? दूसरे दाबदा म, विधि निर्माण में व्यवस्थापिका का बमा भाग है? १ वह अपना ने विधिया के प्रकार प्रधान देशा म—विधिया की प्रकार विता करने का दाबित काशाविका—सिश्चमण्डलीय दोता है। सत्तवीय प्रणाती वाले देशा म व्यवस्थापिकाएँ विधि निर्माण ने सम्ब च म मित्रमण्डल का नतृत्व स्वीकार करती हैं। तिकन इसका अथ यह नहीं है कि कार्यपालिका पर विधिया को प्रकार करने के सम्बाध मतित्व म नहीं है। कर एव व्यव सम्बाधी पुष्टिक विधिया को प्रकारित करने के सम्बाध मतित च नहीं है। कर एव व्यव सम्बाधी पुष्टिक विधिया का स्वावस्थापिकाश वे समक्ष अनितायत प्रस्तुत तिया जाता है। इन मामला म मित्र मण्डल को समक्ष प्रसादित करने कोई स्वत त्रता नदीं होती। येष मामला म मित्रमण्डल विधि विदार की विधियान करने कोई स्वत त्रता नदीं होती। येष मामला म मित्रमण्डल विधि विदार की विधियानमण्डल के समक्ष प्रस्तावित करने या प्रस्तावित न करने म पूण स्वत म हाता है।

संयुक्त राज्य अमरिना की विषय विधि को प्रस्तावित करन के सम्बन्ध में ससदीम प्रणाली के दशा की जपेक्षा अधिक स्वतात्र है। परन्तु निरिवत रूप से वह नहीं कहा जा सकता कि अध्यक्षात्मक देगा में विधिया को प्रम्तावित करने में महर्ष पूण नूमिना व्यवस्थापिका और नायपालिका में में किस के हाथा में हैं। राष्ट्रपति में पीय विधियों में काम सादा अवकर विधियों प्रस्तावित करता है। तिकर राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्तावित विषया पर विधि बनाव या न बनाव का अति माणिय कीयन हो करती है। की प्रमाण की विधि निमाण के सम्बन्ध में मिनियों महत्रपूर्ण पूमिना निरावी है। जा विधि निमाण के सम्बन्ध में अति प्रस्तावित विषय को किस की प्रमाण की स्वत्य की स्वित की स्वत्य की स्वति की स्वत्य की स्वति की स्वत्य की स्वति स्वति

¹⁰ Wheare L C Legislatures, p 99

हैं। लेकिन इतने पर भी व्यवस्थापिका का बहुमत दल विधि निर्माण में महत्वपूण माग लेता है। इगलैण्ड की मांति अमेरिकी काग्रेस को भी कुछ विधिया—यया, राज-कीय धन विधेयक—को अनिवायत पारित करना पडता है।

ह्वीयरे का मत है कि इगलैण्ड एवं संगुक्त राज्य अमेरिका दोना देशों म विधेयकों के सम्बाध में पर्याप्त साम्य है। दोनों ही देशों में व्यवस्थापिका के नेताओं द्वारा व्यवस्थापिका का कायरम निश्चित किया जाता है। परन्तु दोना देशा में एक महत्त्वपूष अन्तर मी है। ब्रिटेन मं व्यवस्थापिका का नेता ही शासन (कायपालिका) का नेता होता है। संगुक्त राज्य व्यवस्थित से अध्यक्षात्मक प्रणाली के कारण व्यवस्था पिका का नेता व्यवस्थापिका का ही प्रमुख नेता होता है, वह शासन (कायपालिका) का नेता व्यवस्थापिका का ही प्रमुख नेता होता है, वह शासन (कायपालिका) का नेता नहीं होता है। भारत में ब्रिटिश व्यवस्था का अनुभमन किया गया है।

विधि निर्माण प्रणाली भी सभी देशा में समान नहीं है। गैर वित्तीय एव वित्तीय विधेयकों के पारित होने की पद्धति एक दूसरे से भिन्न है। शासकीय एव व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा प्रस्तावित विभेयकों के पारित करने की प्रणाली में भी अन्तर

होता है I¹¹

सविधान म सहो। अन भी व्यवस्थापिका द्वारा ही किया जाता है। इगलैण्ड की सास्त को इस सम्बाध मे अनियित्त अधिकार प्राप्त है। सयुक्त राज्य अमेरिका की काग्रेस के होंगो सदमा द्वारा सहोधन-प्रस्तावा का प्रभावकारी होने के लिए पारित होना आवरपक है। मारत म ससद को सविधान के अनेक उपबंधा को साधित करने का अधिकार है। सोवियत सध मे सवाँच्च सोवियत से सवैधानिक सदीधित का अधिकार है। सिव्ट्लर्सण्ड में श्री सविधान के सखीधन म वहा की फेडरल असेम्बसी महस्वपूण माग लेती है।

2 कायपालक एव प्रशासकीय काय

(Executive and Administrative Functions)

व्यवस्थापिका द्वारा समदीय प्रणाली वांसे दशा मे कायपालिका पर निय प्रण रक्षा जाता है। मित्रमण्डल व्यवस्थापिका अथात व्यवहार म निम्न सदन के प्रति अपनी समस्त नीतियो एव कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। अध्यक्षारमण प्रणाली वांसे देशा—यथा, संयुक्त राज्य न्यार्थका—म कायपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तर-दायो नहीं होती लेकिन व्यवस्थापिका का कायपालिका पर नियाजण होता है तथा काय-पालिका व्यवस्थापिका की उपेक्षा नहीं कर सन्ती।

संसदीय प्रणाली वाले देखा में प्रशासन से सम्बिधित विषया पर प्रस्न पूछ कर काम रोको, निदा आदि प्रस्तान उपस्थित करके, बहुस भी भींग एवं धासन के मार्गी भी आलोचना करके कायपालिका पर निमंत्रण रखा जाता है। अविस्वास भा प्रस्ताव पारित हाने पर मित्रमण्डल द्वारा त्यागपत्र देना अनिवाय है।

¹¹ विस्तृत विवरण के लिए दक्षिए अध्याय 12।

समुक्त राज्य अमेरिका म काम्रेस का अन्दोध एव सन्तुतन की व्यवस्था के अधीन काम्यपालिका को नियानित करने के अवसर प्रास्त हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिकी राज्यपित हारा की गमी नियुक्तिया को प्रभावी बनाने के निए सीनट के वी सिहाई बहुमत से उनकी स्वीकृति आवश्यक है। इसी प्रकार, विदेशा से का गमी सिम्प्रेस को भी प्रभावकारी बनाने के लिए 2/3 बहुमत से उनका सीनेट द्वारा अमेरिक आवश्यक है। युद्ध की घोषणा एव धान्ति स्थापना की भी शक्ति अवस्थाविम में होती है। दूसरे शब्दों में, वेदिश्व एव पुरक्षा सम्बन्धी विषयो म भी स्थवस्थाविक को व्यापक अधिकार प्रान्त हैं। इसर्वण्ड म सिन्ध के मामले में व्यवस्थाविका से प्राप्त हैं। इसर्वण्ड म सिन्ध के मामले में व्यवस्थाविका (तीनट) की अनुमति आवश्यक होती है। स्मरणीय है कि अमरिका म सिन्ध के मामले में व्यवस्थाविका (तीनट) की अनुमति आवश्यक होती है। स्मरणीय है कि अमरिका में सिन्ध के मामलो म कामलो म वाम्य है होना मदनो के शक्ति प्राप्त होती है। स्मरणीय है कि अमरिका में सिन्ध के मामलो म लिए में सिन्ध का साम्य सी अधिकार प्राप्त हो है अपितु उसके एक माम—सीनेट—को हो सिंध सम्बाधी अधिकार प्राप्त हो है कि काम समस साम एव युद्ध के तिए आव स्वक वित्तीय अनुदान एव विदेश विमाग के अनुदाना को अस्वीकृत करके अध्वस्थ स्व हम मामलो म हस्तक्षेप कर सकती है।

युद्ध की घोषणा के सम्बाध मंदी प्रकार के देश है। इंगलण्ड एवं राष्ट्र मण्डलीय देशा म नायपालिका द्वारा ही युद्ध नी घोषणा की जाती है। ससद से इनर्न स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। स्वीडन भी इसी श्रेणी म आता है। तिन दूसरी थेणी के दशो म सयुक्त राज्य अमरिका प्रमुख देश है। अमेरिकी कांग्रस ना है युद्ध की घोषणा का अधिकार प्राप्त है। फ्रान्स के पाँचवें गणराज्य के सविधान है अनुसार युद्ध की घोषणा का अधिकार फ्रेंच ससद को है। लेकिन इगलैण्ड एवं उष्ट वग के देशा में ससद अप्रत्यक्ष रीति स अर्थात आवश्यक धन की स्वीकृति अपवी अस्वीकृति द्वारा इस अधिकार को नियात्रित करती है। समुक्त राज्य अमरिका की काग्रेस को युद्ध की घोषणा का सबैधानिक अधिकार तो है लेकिन राष्ट्रपति बिद्ध मीति के समालन से ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है कि कांग्रस की युद्ध की घायणा करना अनिवाय हो जाये । कुद्र व्यवस्थापिकाका को राज्य के प्रमुख विष कारियों को चुनन का अधिकार प्राप्त होता है। उह निर्वाचन सम्बंधी कार्यों की मणा दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्विट्जरलैंग्ड म फेडरल असम्बली (सपीय व्यवस्थापिका) द्वारा परिसाध के राष्ट्रपति तथा सधीय कायपालिका परिषद क (फडरते गाउ सल) क सदस्या, यायाधीशा एव प्रधान सनापति का निर्वाचन किया जाता है। भारत व राष्ट्रपति का निर्वाचन करने वाले निर्वाचक-मण्डल व सदस्या म भारतीय ममद रे दोना सन्ना क निवाचित सदस्य भी होत है। भारत के उपराष्ट्रपति ना निवाचन नी भारतीय ससद द्वारा किया जाता है। फास के राष्ट्रपति का निवीवन वहाँ व दोना सदना की संयुक्त बैठर म होता है। संयुक्त राज्य अमरिका म राष्ट्रपति पद वे विसी भी प्रत्याक्षी को बहुमत प्राप्त व होन पर प्रतिनिधि समा को यह अपि

कार प्राप्त है कि वह सबसे अधिक मत पाने वाले प्रथम तीन प्रत्याशियों म से किसी मी एक प्रत्याची ना राष्ट्रपति चुन ले। उपराष्ट्रपति पद के लिए मी यदि किसी प्रत्याची की स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो सीनेट को सबसे अधिक मत पाने वाले दो प्रत्याचाया में से किसी एक को उपराष्ट्रपति निर्वाचित करन का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, कोंग्रेस के दोना सन्वाच को अपने सदस्यों की निर्वाचन सम्बंधी योग्यताएँ, अपने निर्वाचन सम्बंधी योग्यताएँ, अपने निर्वाचनों के सम्बंध म निर्याच कोंग्रिकार प्राप्त होता है।

व्यवस्यापिकाओं का एक महत्वपूर्ण काय खासन की आसोचना करना होता है। महत्वपूर्ण सावजिनक मामला पर व्यवस्थापिका मं बाद विवाद होते हैं। व्यवस्था-पिकाएँ जनता की शिकायता एव लोकमत को प्रकाश मं लान का एक सबल माध्यम है। जान स्टुअट मिल के अनुतार वे 'शिकायता की समिति एव 'विचारा के सदन' के रूप म काय करती हैं। 12

3 वित्तीय काय

(Financial Functions)

आधुनिक राज्यों में ब्यवस्थापिका का राज्य के वित्त पर पूण नियात्रण होता है। सभी सीकता निक देवा म यह नियम है कि राजकीय में से एक पैसा भी ब्यवस्थापिका की स्वीकृति के विना व्यय नहीं किया जा सकता और जनप्रतिनिधियों की स्वीकृति के विना व्यय नहीं किया जा सकता और जनप्रतिनिधियों की स्वीकृति के विना न कोई कर ही लगाया जा सकता है। वित्त सम्बन्धी सिक्तया सामायत निम्म सदन म ही अधिध्ठत होती है और इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा सामजातक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते है। समस्त वित्त विधेयक निम्म सदन में ही सक्षप्रथम प्रस्तुत किये जाते है। यह वर्तमान समय में एक सुस्था-पित परम्परा है। इगलैण्ड, अमेरिका, फ्रान्त, कनाडा और मारत आदि देवा यही परम्परा है। समायत वित्त विवेषका के समन्य में दितीय सदन को प्रथम सदन के समान अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन अमेरिकी सीनट इसका अपवाद है।

कायपालिका द्वारा वाधिक आय ख्याय का विवरण (वजट) तैयार किया जाता है और व्यवस्थापिका के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। वह कायपालिका द्वारा प्रस्तावित मदा म कटौती कर सकती है। व्यवस्थापिका द्वारा जिस रूप में वजट पारित किया जाता है उसी प्रकार एय स्वीकृत मदो में ही धन व्यय किया जा सकता है। व्यवस्थापिका यह भी देखती है कि कायपालिका उसके द्वारा स्वीकृत घनराधि को निश्चित नियमों के अनुसार ही व्यय करती है। वत वह लेखा-परीक्षण (audit) भी करती है। इसके लिए व्यवस्थापिका समितिया का निर्माण करती है। इसके लिए व्यवस्थापिका समितिया का निर्माण करती है। जैस साव-

¹² They debate great issues of public concern The constitute 'a ground inquest of the nation They act as what John Stuart Mill called a committee of grievances' and 'a congress of opinions —Wheare, K. C. Legulaturer, p. 1

जनिक लेखा समिति एव अनुमान समिति । इसके अतिरिक्त, महालेखा परीक्षक नी वार्षिक रिपोट ससद के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत की जाती है।

4 न्यायिक कार्य

(Judicial Functions)

व्यवस्थापिका द्वारा अनेक देशा मे "यायिक काय किये जाते हैं। इगलण्ड की ससद का द्वितीय सदन--लॉड सभा--देश का सर्वोच्च अपीलीय 'यायालय है । सपुक्त राज्य अमेरिका मे राष्ट्रपति, जपराष्ट्रपति, न्यायाधीशा एव सधीय अधिकारियों ह विरुद्ध महाभियोग की जाच सीनेट करती है। प्रतिनिधि सदन द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव किया जाता है। ऐसी स्थिति म सर्वोच्च यायालय का मुख्य न्यायांवीय सीनेट की अध्यक्षता करता है। मारतीय ससद को भी राष्ट्रपति के विरद्ध महासियोग की जाच करने का अधिकार है। फास में राष्ट्रपति एवं किसी मानी पर महासिया लगाये जाने पर 'काउ सल ऑफ रिपब्लिक' न्यायालय का काय करती है।

व्यवस्थापिका का आकार

विधि निर्माण मे वाद विवाद एव विचार विमश विशेष एव महत्वपूर्व भूमिका निभाते है। सामायत विचार विमश के सम्बाध में एक स दो मले होते हैं। जब विवेच्य विषय वासम्बाध राष्ट्र से हो, तो दो की अपेक्षा दो सी की सर्वी अपेक्षित है। दूसरे शब्दो मे, विधि निर्माण के हेतु व्यवस्थापिका म पर्याप्त सहस्य सख्या होनी चाहिए जिससे समाज के सभी वर्गों एव हितो तथा विचारा का सर्पु^{वर} प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। ऐसी अवस्था मे ही विधानमण्डल द्वारा निर्मित विधि व्यापक स्वीकृति पर आधारित हो सकती है। व्यवस्थापिका की सदस्य-सस्था ह निर्धारण के सम्ब व में किसी सिद्धात या नियम की स्थापना सम्मव नहीं है। प्रत्यक देश के आकार या क्षेत्रफल, जनसंख्या अथवा अय आवश्यकताओं के अनुसार उनरी थ्यवस्थापिकाओं के जाकार या सदस्य-सख्या म भी अन्तर होता है। 1789 ई की फास की व्यवस्थापिका सबसे वडी व्यवस्थापिका थी। इसम 1,200 सदस्य वे। जनता द्वारा निवाचित आधुनिक सदना म एक तरफ वडे अर्थात् अधिक सदस्य-स^{द्धा} वाले सदन हैं ता दूसरी तरफ छोट अर्थात् कम सदस्य-सस्या माले सदन हैं। उदाहरण के लिए, इंग्लैण्ड की कॉम स समा म 630 सदस्य हैं। फास की राष्ट्रीय सना म 482, इटली के चेम्बर जाफ डेपुटीज में 630, मारतीय लोक्समा म 525, जम^द बुन्डस्टेग म 496, अमरिकी प्रतिनिधि सदन म 435, सोवियत रूस की सध सावियन म 791 सदस्य हैं। यह सभी सदन आकार म बहुत बड़े हैं और जन-समाओं है प्रतीत होत हैं। बहदाबार हान के कारण यह मुचार रूप सं अपने दायित्वा वा सम्पा दन नहीं कर पात है। जहाँ एस बहु मदस्य-सस्या वाल सदन हैं, वहाँ दूसरी वर्ष अनेन सदना भी सदस्य सध्या बहुत नम भी है। उदाहरण के लिए, समुक्त राज्य अमेरिका में दा राज्या निवदा एवं हिलावार नी सीनट म नेवल 17 सदस्य हैं और इन राज्या की सीनट एक समिति सी प्रतीत होती है। स्विट्जरलण्ड की रा^{ट्टीव}

परिषद (National Council) म 196 सदस्य है और राज्य परिषद (Council ा प्रमाणिक के व्यक्तिया में 159 एवं आस्ट्रेलिया क प्रतिनिधि सदन म 121 सदस्य है। कुछ व्यवस्थापिकाएँ आस्वयजनक रूप से बडी व्यवस्थापिका | 235 हैं, जैते समुक्त राज्य अमेरिका के यू हैम्पशायर के प्रतिनिधि सदन म 400 सदस्य हैं जबकि वहाँ की जनसङ्घा 6 लाख है। इसरी तरफ युपाक राज्य की जनसङ्ग र जार प्रशास नगण्या ५ गाव र १ द्वारा परम द्वारा परम है । 1 करोड 70 नास है नेकिन उसकी असेम्बली म केवल 150 सदस्य है । द्वीपरे के अनुसार मह व्यास्त्र के हैं कि 'समुक्त राज्य अमेरिका एवं मारत जैस बहुद जनसरमा ्रवार पर पार्टिका के सहना की सदस्य-संस्था ब्रेट ब्रिटेन, इटली एवं फास के परना की तुलना म काफी कम हैं। उपयुक्त होना देशों के सदना हारा अपेकाहरत अधिक जनता का प्रतिनिधित्व किया जाता है। यह सत्य है कि संशासक राज्य होंगे के कारण एव भारतीय जनता को राष्ट्रीय एवं राज्या की व्यवस्थापिकाओं दोना ही ा प्रतिनिधित्व प्राप्त है। बेकिन फिर भी यह विचारवीय है कि स्या ग्रेट बिटेन इंटली एवं क्रांति के विद्यापी सेवन विद्योप वहें हैं या अमेरिकी एवं मारतीय व्यवस्थापिका के सदन विशय छोटे हैं।'28

इसके अविरिक्त द्विसदनारमक व्यवस्थापिका वाले देशो म दिवीय सदन की सदस्य-वेस्या कम होती है । इंगलैंग्ड को लॉड समा इंतका अपनाद है । उसकी सदस्य-संस्था काम सं समा है। राज्यक का चार का राज्य जा राज्य है। जिस्सा के समी संवस्य उसकी बठका म माम नहीं लेता सोवियत सम की मुप्रीम सोवियत के दोनो सदाना ज्यमा ४०मा भ भाग गहा चया चावनक चन भा पुनान चावनक में सोनियत) एवं उच्च सदन (सङ्ग्रेयतामा की सोनियत) की विस्त मेरना म बहुत अधिक अंतर नहीं हैं। तोवियत उच्च पदन की सदस्य सरमा विषय प्रत्या भ बहुत आधक अ तर नहा ह । प्राप्त्रपत ७०५ प्रत्य प्रवश्य प्रत्य प्र स्विद्यर्तिष्ठ एवं मारत के हितीय सदना की सदस्य-सर्वा प्रथम सदन की सुलना म कम है। संदुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट की संबंध्य-संख्या कवल 100 है।

हों पर का कथन है कि अधिकास दशा की व्यवस्थापिका के सदना—विशेषकर निम्म सदना की सदस्य साथा सामा यत 100 से 300 के मध्य म है। 11 उहाने वेपन मन के समयन म कनाड़ा के हीजस ऑफ काम स (265 संदर्स), वेल्जिय म के निम्म सदन (212 संदर्भ), स्विस निम्म सदन (233 सदस्य), स्विट्यस्वीयः की भाव वाज (170 वावस्त्र), वावस्त्रभः (४२४ व्यक्त्र), भावस्त्रभः (४२४ व्यक्त्र), भावस्त्रभः (४२४ व्यक्तिः), इतिस (179 सदस्त्र) के उदाहरण दिने हैं। यूजीसण्ड के निम्न सदन प्रतिनिधि पदन की पदस्य-प्रस्था केवल 80 है। द्वीयर का करन कि विधिक्त त्राम् पदन भा वदर्य-पद्धा कवल ०५ हा ख़ावर का कवन का वावकाच त्रिम तदना की तदस्य सहया 300 ते विभिन्न नहीं है। यह कैवल कम जनस्या एव होटे उपयुक्त देशा के सदम म हो सत्य हैं, वेकिन इंगलेख, भारत, लग, का स अमिरका आदि देशों के निम्न सदना की सदस्य-सस्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। 13 Wheare K C op cut PP 3 4
Wheare K C op cut PP 3 4

14

ह्रीयरे का मत है कि व्यवस्थापिका की सदस्य सस्था क पत्तस्वस्य उन्हें सगठन एवं काय-पद्धित सम्ब धी जनेक महत्वपूण समस्थाएँ उत्पन्न होती हैं। उवाहण के लिए, वडे सदन के समक्ष प्रथम समस्या स्थान की होती है। इगलण्ड की कार्य्य समा का भवन अपनी सदस्य सस्था को देखत हुए छोटा है। 1943 ई म उनके प्रविचाय के समय इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था कि कॉमन्त क भवन को इतना वडा बनाया जाय कि सभी सदस्य स्थान पा सके। इगलण्ड अपवार है अपया सभी देशा के सदना मं सदस्यों के बैठने की समुचित व्यवस्या होती है।

व्यवस्थापिका सभा की कितनी सदस्य-सस्था उचित है ' काइतर के बहुवार इस सम्ब ' य म विचारणीय वात यह है कि प्रतिनिधियों की सस्था जितती मिषक होते उतते ही छोटे निर्वाचन क्षेत्र होंगे और इससे जनता को अपसाकृत अधिक प्रतिनिधित प्राप्त होगा । अेच्छ विधि के निर्माण के लिए प्रतिनिधित्व का प्रधान महत्व है। बर्ति अधिक सदस्य सस्या के कारण प्रभावशाली काय-पद्धित को अपनाना कठित हो बात है। अत पूण प्रतिनिधित्व को अधिकतम महत्व दिया जाना चाहिए । काय-वर्धि सम्ब धो आपत्ति के सम्ब ध म फाइनर का मत है कि 'विधि निर्माण को अधिक सम्ब धो आपत्ति के सम्ब ध म फाइनर का मत है कि 'विधि निर्माण को अधिक काम समितियो द्वारा विचा जाता है। अत फाइनर न आधुनिक लोकत त्रीय पत्रो के निम्म सदन की सस्या 800 निश्चित की है। उसने सदस्य-सस्या के बढ़ान वा उम्र सम्ब के किया है । 'नियोजन के युग म व्यवस्थापिका को वहा होना चाहिए। प्रदि वय म 365 दिना का नहीं बढ़ाया जा सकता तो अपन काम मार को वहां करते के लिए व्यवस्थापिका क सदस्यों की सर्या म वृद्धि की जानी चाहिए।'16

व्यवस्थापिका का कार्यकाल

व्यवस्थापिका के कायकाल या अविष की समस्या इस मूल प्रश्न से सम्बंधि है कि प्रतिनिधित्व कसा होना चाहिए ? यदि प्रतिनिधि सदन जनता की इच्छा का समित प्रवाद करता होना चाहिए ? यदि प्रतिनिधि सदन जनता की इच्छा का समित प्रवाद होना चाहिए । जॉन आदम (John Adams) का करन या कि अनिस्ति सिद्यात के निर्माण के समय यह विचार बहुत लोकप्रिय या कि प्रयस्थापिकाओं का कम-वन छोटा होना चाहिए । 'जहां चापिक चुनाव नहीं होत बहां अव्याचार का आरम्भ हो जाता है।' अत अमिर्ट्स के सिद्यात के निर्माण-वाल म मुख्य प्रतिभाग करा स्वाद से स्वाद का या, न कि शासन म शामता से । शासन की शामता की उद्याचार स रक्षा ना था, न कि शासन म शामता से । शासन की शामता की उद्याचार स निर्माण-वाल म मुख्य प्रतिभाग चिवाद म मिच्यान न निर्माताओं न स्वीना कर तिया या । असमय की परित्य तिया म एमा सम्मव था। 'कहरनिस्ट' (The Federalist) नामक रचना म प्रतिनिध सदन कर पुनर्योध नामकाल की परता दिया म एम सम्मव था। 'कहरनिस्ट' (The Federalist) नामक रचना म प्रतिनिध सदन पर नियं शास हो हो। उस ममय सदन पर नियं शास की कम अवस्यनता थी। सिंवान

¹⁵ Finer, H op at, p 390

हारा अय सधीय अगो के माध्यम से प्रतिनिधि सदन की शक्ति पर पयाप्त प्रतिव के लगा दिये गय थे। (2) योग्य विधायक बनने के लिए विकि एव उसके निमाण का पर्याप्त ज्ञान होना आदस्यक है। यह ज्ञान व्यावहारिक अनुभव से ही सम्भव होता है। अत अमेरिको सविधान निमाताओं ने एक वय के स्थान पर दिवर्षीय कायकाल को स्वीकार किया। (3) इसके अतिरिक्त, लम्बा कायकाल व्यवस्थापिका के विधटन एव मबीन निर्वाचन सम्ब धी कठिनाइयो ते भी मुक्ति प्रदान करता है।

यरोपीय देशा की व्यवस्थापिकाओं के कायकाल मित्र मित्र है। इगलैण्ड का निम्त सदन-कामास सभा-का कायकाल पाच वप है। 1911 ई के प्रव इसका कॉयकाल सात वर था। 1641 ई के अधिनियम के अनुसार इंगलण्ड की ससद का कायकाल केवल तीन वप था । 1716 ई मे सप्तवर्षीय अधिनियम (The Septennial Act) के अनुसार इसका कायकाल सात वय कर दिया गया था। संसदीय अधिनयम 1911 ई के पारित होने पर कॉम स समा विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली सदन बन गया है। लाड समा की शक्तियाँ सीमित कर दी गयी है। अत कॉम स पर अपेक्षा-कृत अधिक निय त्रण की आवश्यकता अनुभव नहीं की गयी। जनमत संग्रह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। अत कॉम स समा पर निय त्रण का केवल एक ही साधन रह जाता है और वह है कि कॉम स समा के काय-काल की कम कर दिया जाय। इस व्यवस्था का विरोधी दल के कुछ सदस्यों ने इस आधार पर विरोध किया है कि शीघ चुनावों के कारण दलीय नियानण बढ जायेगा और मित्रमण्डल की शक्ति मे अधिक वृद्धि हो जायेगी तथा व्यक्तिगत सदस्यों की स्वत नता सीमित हो जायेगी। इसके अतिरिक्त ससदीय जीवन के लर्चे म विद्व हो जायगी। अनुदारदलीय सदस्यो के दबाव के कारण अधिनियम म यह धारा जोड़ दी गयी है कि अकेले कॉम स समा एव राजा के द्वारा ससद के पाच वय के कायकाल मे वृद्धि नहीं की जा सकती। लेकिन फाइनर के अनुसार आज यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या कॉम स समा का कायकाल पाच दय से कम नहीं होना चाहिए?

फी स म व्यवस्थापिका का काय काल पाच वप था। झासन व्यवस्थापिका की मग नहीं कर सकता था। इगलैण्ड मे मिनमण्डल के परामदा पर नाउन के द्वारा कामन्त समा को कायकाल के पूच मन किया जा सकता है। फान्स में अन्दूबर 1946 ई के निवाचन अधिनियम की धारा 36 के अधीन सस्स्थ पीच चप के लिए चून जाते हैं। 1919 ई के जमनी के वीमर सविधान के अन्तयत सधीय विधानमण्डल मा कायकाल 4 चप या लिन सासव को उसे उसके पूच मा करने का अधिकार प्राप्त था।

स्विटवर्सण्ड की राष्ट्रीय समा (निम्न संदन) चार वप ने तिए निर्वाचित होती है। तेकिन इसको काय-काल के मध्य म विषटित नहीं किया जा सकता। परिचमी जमनी के निम्न सदन (Bundestag) के सदस्य चार वप के लिए वयस्न मताधिकार में भोभार पर निर्वाचित किये जाते हैं। इटली के नवीन सविषान के अन्तगत वैम्यर आफ डेयुटीज (Chamber of Deputies—निम्न सदन) का नायकाल 5 वप है। सोवियत रूस की सर्वोच्च सोवियत का कायकाल 5 वप है। सर्वोच्च सोवियत के दोनो सदनो का निर्वाचन एक साथ ही होता है। जापान के नवीन सिवधान न व्हं की व्यवस्थापिका (Diet) के निम्न सदन—प्रतिनिधि सदन—का कायकाल 4 वर्ष निष्चत किया गया है। गारतीय लोकसभा का कायकाल 5 वप है। मित्रमध्य इसको कायकाल के पूब विघटित करने की माग कर सकता है। आरट्रेनिया कं प्रतिनिध सदन का कायकाल 3 वप है। कनाडा के निम्न सदन—काम स समा—का

कायकाल भी 5 वप है। इसे भी कायकाल से पूव विघटित किया जा सकता है। फाइनर चार वय के कायकाल को उचित मानता है और उसका ही पक्षपती है। उसके अनुसार चारवर्षीय कायकाल दला पर नियानण की दृष्टि से आवस्पर है। दलों की शक्ति में विद्धि के फलस्वरूप व्यक्तिगत सदस्य की स्वतानता सीमित हैं। गयी है। सत्ताघारी नेताजो को आत्म-सन्तोष तथा निर्वाचन के धक्के से ही जगाग व सकता है एव जैसे जैसे निर्वाचन समीप आता जाता है वे लोकमत के प्रति अधिक संवेध होते जाते हैं। फाइनर के अनुसार "इगलैंग्ड की हब्दि से 3 वय का कायकाल विधा यक के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्ति हेतु कम है लेकिन 5 वप का कायकाल अधिक है। अत वे 4 वप की अवधि को सहज ही स्वीकार कर सकते है।" काइनर निर्वाचन की अवधि को कम करने के पक्ष मे एक और सबल तक देता है। आप निर्वाचको एव मतदाताओं का सीधा सम्बाध है और महत्वपूण विषयों के निष्य ब्यवस्थापिका के वाहर ही किये जाते हैं अत राजनीतिक इब्टि से निर्वाचका का योग्य होना अस्य त आवस्यक हो गया है। यह तभी सम्मव हो सकता है जबकि राजनीति सस्याएँ निर्वाचका को अपने दायित्व मे दीक्षित कर । अत व्यवस्थापिका के कामकार के कम होने पर जनता से शीघ्र परामश सम्भव होता है और विभिन दला को पी वर्तित परिस्थितिया के अनुकूल अपने लक्ष्यों म परिवतन करने का अवसर मिलता है। निर्वाचको को भी राजनीतिक शिक्षा मिलती है। जनता को विभिन्न दलों के आश्व सनो एव क्रियाकलामा के परीक्षण के अपेक्षाकृत अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। ^{अहा} फाइनर का कथन है कि 'ब्यवस्थापिका का चारवर्षीय कायकाल एक आधुनिक आ^द स्यक्ता है। विशेषकर राष्ट्रीय नियोजन की बढती हुई प्रवृत्ति के कारण शासन के कार में जिस अनुपात म बद्धि हो रही है उसी अनुपात म उस पर लोकप्रिय नियापण ही भी आवश्यक्ता है। व्यवस्थापिका के 4 वय के कायकाल के पूर्व व्यवस्थापिका की विषटन परिस्थितियां वद्य यदि आवश्यक हो जाय तो सविधाना में उसकी भी उ^{दित} व्यवस्था होनी चाहिए।⁷¹⁶

^{16 &#}x27;A four year s term (of a legislature) is a modern necessity a longer term is madvisable because the broder the activity of government. the more opportunities ought there to be for reference back to the citizens the duration be set for four years with earlier dissolution if circumstances require it.

Finer, H op at , p 390

व्यवस्थापिकाओं का विघटन एव उप-चुनाव

ध्यवस्पापिका से सम्यन्धित दो महत्वपूष प्रश्न उसके विषयन एव उप-चुनावा स हैं (1) क्या व्यवस्थापिकाओं को उनके कायकाल के पूर्व विषयित किया जाना चाहिए? एवं (2) इस प्रकार का विषयन एवं उप चुनाव किन परिस्थितियों से उनित हैं ? संयुक्त राज्य अमेरिका की काग्रेस का कायकाल निश्चित है और उसे घटाया या खाया नहीं जा सकता । 1919 ई के जमनी के बीमर सविधान एवं कात के चतुष्य गणतानीय सविधान में अवधि के पूर्व व्यवस्थापिका के विषयन की व्यवस्था थी। इगलैण्ड में मी काउन ससद को अवधि के पूर्व विषयित कर सकता है। अनेक अवस्ति पर प्रिटश ससद को अवधि के पूर्व विषयित किया गया है। मारत के नवीन सविधान के अन्तगत प्रथम बार 1970 ई में प्रधानमन्ती इदिरा गांधी के परामश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसमा को विषयित किया गया और मध्याविधि निर्वाचन हुए थे।

इगलैण्ड म ससद को विघटित करने का अधिकार काउन को प्राप्त है। लोक-तान के विकास के पश्चात राजा के व्यक्तिगत अधिकार सस्यागत काउन को हस्ता त-रित हो गये है और विघटन का अधिकार मन्त्रिमण्डल को प्राप्त हो गया है। अब मन्त्रि-मण्डल राजा को देश हित म विघटन का परामश देता है। प्रश्न यह है कि इगलण्ड म मिनमण्डल किन कारणो से ससद के विघटन का प्रस्ताव करने के लिए वाध्य है ? 19वी सदी म केवल एक ससद (1867-73 ई) ही अपने पूर कायकाल-पय त काय कर सकी थी। इस काल म कॉम स सभा मे उदार दल का बहुमत था। इस निर्वा-चन के पूर्व इंगलण्ड की ससद के दलों में प्राय धार्मिक, वदेशिक एवं व्यापारिक प्रश्नो पर मतभेद हुआ करते थे और एक दूसरे मे परस्पर तीव विरोध हुआ करता या। बहुमा बहुसस्यक एव अल्पतरक तता में इन वर्षों में अधिक से अधिक बीस मता का जिर होता या। 1873 ई के पश्चात बहुमत दलों को एक अप कठिनाई का सामना करना पड़ा। इमलैण्ड के विभिन्न दल आगरलैण्ड की स्वताजता के प्रश्न पर विमाजित थे। इस समय इगलैण्ड की राजनीति में स्थायित्व आयरिक शासन के 60 सदस्यों के गुट पर निभर रहता था। 1885 ई म इस गतिरोध के अंत के लिए उदारवादिया एव अनुदारवादियो दोनो न ससद को विघटित करने का निश्चय किया था। ब्रिटिश संसद के अपनी अवधि के पूच विघटन के कुछ, उदाहरण निम्नवत् हैं 1905 ई म बालफोर द्वारा त्यामपन, 1910 ई म लॉबड बॉज के परामश पर सामा-जिक एव आधिक सुधारी पर जनता की राय जानने हेतु ससद को विघटित किया गया जिसकं फलस्वरूप लॉड-समाकी शक्तियाँ कम हुइ , 1918 ई मे प्रथम निश्ताः युद्ध के युद्ध विराम के पश्चात ससद का विघटन, सरक्षण के प्रश्न पर 1921 🕯 भें वाल्डविन का त्यागपन, 1931 ई मे रैम्से मकडोनल्ड ने श्रमदस से पुषक सीक्र राष्ट्रीय सरकार का नेतत्व किया । राष्ट्रीय सरकार म अनुदार, उवार ५१ भगना सदस्य शामिल थे जिनके हितो मे परस्पर विरोध था । मुक्त स्थापार नेपाम

240 | आधुनिक शासनतः त्र

की नीति के प्रश्न पर दला में मतभेद बढत गये। अंत म ससद को विषटित गर नवीन चनाव हुए थे।

फाइनर¹⁷ के अनुसार इंगलैण्ड के इतिहास से हम इस समस्या का कोई सप्ट उत्तर नहीं मिलता । लेकिन यह जवस्य ज्ञात होता है कि वहाँ किन परिस्थितियाँ व विषटन हुए थे । वे परिस्थितियाँ निम्नलिखित है

(1) शासन जब किसी विधेयक को पारित करना आवश्यक समभता हा और विरोधी दल द्वारा उसम गतिरोध उत्पन्न कर दिया गया हो ।

(1) सरकार को जब अपनी स्थिति का ठीक ज्ञान न हो या उस यह विख्ता

हो गया हो कि जनता का विश्वास उसे प्राप्त नहीं है।
(111) सरकार के समक्ष जब कोई ऐसा मीलिक अयवा महत्वपूर्ण ^{सीति} सम्बन्धी प्रस्त विचारणीय हो जिस पर जनता की राय लेना आवश्यक हो।

जमनी के वीमर सविधान (1919-1933 ई) म विघटन की व्यवस्या थी। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया था, लेकिन सविधान के अनुसार एक कारण के लिए केवल एक बार विघटन सम्मव था। वीमर सविधान के अन्त^{गह} राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित होता था । मिनमण्डल मी जनता द्वारा प्रत्यक्ष निवाचित होता था। ससदीय व्यवस्था की स्वीकृत एव मा य व्यवस्था के कारण मि तमण्डल को भी राष्ट्रपति के समान ही व्यवस्थापिका को विषटित करने ही अधिकार प्राप्त हो जाता था। अत प्रश्न यह या कि मिनमण्डल विघटन का आरी दे सकती थी या नहीं ? जिन अनेक मित्रमण्डलों ने विघटन की माग की थी, उहें यह अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। जमनी के ससदीय जीवन म अवरोध की तीन वर्ष स्थाओं में ही राज्द्रपति द्वारा विघटन स्वीकार किया गया । राज्द्रपति हिण्डेनवर्ग ने व्यवस्थापिका के विघटन की माग को अस्वीकार कर दिया था। उसने मिनमण्डल ही पदारूउ रहने एव कम विवादयुक्त या विवादहीन नीतियो के अनुसार काय करने न परामश दिया था। इन्ही राष्ट्रपति हिण्डेनवग ने 1932 ई म प्रधानमात्री बूर्निंग ने त्यागपत देने का आदेश दिया था । जमनी क ससदीय जीवन मे प्रतिक्रियानादियां नाजी अनुदारवादी एव साम्यवादी—के गुट के कारण विघटन की अनेक घटनाए घटी थी। प्रथम विघटन 1924 ई म हुना था। नवीन निर्वाचन के पश्चात भी समस्या नहीं सुलभी। पहले की माति ससद म अनेक दल थे और उनकी स्थिति कमबार थी। इसी वप अक्टूबर 1924 ईं में ससद का पुन विघटन हुआ था। जुर्ताई 1930 ई म बूनिंग के मिथित मि त्रमण्डल को प्रतित्रियाबादी दलों के गृट कं विराध के कारण विघटित करना पढा था। ससद के निष्प्राण होने के कारण इन विघटनी

का सस्य स्पप्टत स्थायित्व था अत ये प्रगसनीय थे। लेकिन इसी अस्त ना प्रयोग फरवरी 28, 1933 को हिटलर द्वारा प्रधानमध्यी बनन के बाद किया गया और

¹⁷ Finer, H op at , p 393

संसद को विषटित करने की उसकी माग्र को हिण्डेनवग ने स्वीकार कर लिया । फल-स्वरूप जमनी म लोकतात्र का विषटन हो गया और अधिनायकतन्त्र का उदय हुआ ।

पृतीय फेन्च गणराज्य के सविधान के अतगत राष्ट्रपति को सीनेट की अनुमित से नेम्बर ऑफ डेपुटीज को विधिटत करने की शक्ति प्रवान की गयी थी। इसका
केवल एक वार 1877 ई में राजत त्रवादी राष्ट्रपति मैकमोहन ने प्रयोग किया एव
जुलियस साइमन को त्यागपत देने के लिए वाच्य किया। चेन्बर ऑफ डेपुटीज म
जिसमे गणत त्रवादियों का बहुमत था इससे तीज अस तोप उत्पन्न हो गया। फलस्वरूप
राष्ट्रपति ने सीनेट से विधटन का समयन करने को कहा। निस्स देह यह सवधानिक
अधिकार का दुश्ययोग था। फेन्च राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग एक प्रकार से
जनता के विरुद्ध किया था। इसके पश्चात प्रणराज्य काल में विधटन के अधिकार का प्रयोग नहीं किया था। चतुष्य फेच गणराज्य के अधीन कुछ सीमाओं के
जित्रत सहस्व के विधटन की व्यवस्था थी।

मारत म इिंदरा गांधी ने लोकसभा के विघटन की मांग 1970 ई में विशेष परिस्थितियों में की थी। कम्रिस दल म मतभेद उत्पन्न हो गये थे। फलस्वरूप दल विघटन की स्थित में था। प्रधानमन्त्री ने अपनी नीतियों के सन्व ध में सीधे जनता से स्वीकृति लेने का निश्चय किया। प्रधानमन्त्री की साथ पर नवीन निर्वाचन हुए जिनमें उन्ह, उनके दल तथा उनकी नीतियों को असाधारण सफलता मिली थी। इस विघटन को मांग को निजी स्वाध एक लक्ष्य से प्रेरित नहीं कहा जा सकता। यह एक स्वस्य परस्पर है। 1970 ई के मध्यावधि निर्वाचना के फलस्वरूप इब एव स्थायों सरकार का निर्माण हुआ था।

व्यवस्थापिका को प्रभावित करना

व्यवस्थापिकाओ पर व्यक्तियो एव सस्थाओ का निरंतर प्रमाव पढा करता है और इन सुत्रा से ये अत्यधिक प्रमावित होते रहते हैं। ह्वीयरे के अनुसार विधायका को निम्नतिखित तरीका से प्रमावित किया जाता है

- (1) निर्वाचन-काल में विधायको द्वारा या उनके दलीय नेताओ द्वारा निया-चका को दिय गय आदकावन । चुनाव घोषणा पत्र म मतदाताओं को अनेक बाता के सम्बंध म दल की तरफ से आदबातिम दिया जाता है। विधायका द्वारा दनकी उपधा नेहीं को जा सकती। अधिकाम विधायक किसी दल के सदस्य होते हैं। दलीय साम्या द्वारा नियाचित विधायकों के काय दलीय अनुगासन एवं नियन्त्रण द्वारा प्रमाधित किये जात है। उन्हें विशिष्ट मामला म क्सि प्रकार अपना मत दना है, इसने सम्बद्ध म मुख्य दला द्वारा स्पष्ट निर्देश दियं जात हैं। हर देग एवं दल की नीति दो मम्बद्ध म निया होती है। सामा यत प्रत्येक दल द्वारा अपन विधायका स दलीय नीतिया । समध्य से अपका की जाती है।
- (2) विधायका का जनता म सम्यक्त होता है। वह अपन निवायन-सेन सदस्या क विचारा में प्रमावित होना है। तार एवं पत्र, आवदन-यत्र (petitio

जनके विचारो एवं कार्यों के विरोध अधवा समयन म व्यक्त मत, विरोध प्रदर्ण. व्यवस्थापिका के समक्ष प्रदर्शन आदि विधायकों को प्रमावित करन के अन्य सार्थन हैं।

(3) अमेरिका म काँग्रेस को प्रमाधित करने के लिए प्रमाव-समूहा वा सगर किया जाता है। काँग्रेस के सदस्या का प्रमाधित करने की प्रित्रया एव प्रमाधी की Lobbying की साथ दो जाती है। इन प्रमाव-समूहा द्वारा व्यवस्थापिक के सत्त्व की स्थायति करने के लिए अनेक प्रकार के तरीके प्रयोग म लाय जात है। उदाहर के लिए, विधायतो के चुनावा म आर्थिक सहायता देना, विभिन्न के प्रशेश से उमीन्यार खंडे करना, निर्वाचन-क्षेत्र को जनता को सन्विधित प्रश्न के पक्ष या विश्वस में प्रचीव करने हेतु विधायका को पत्रादि या प्रचार-सामग्री मिजवाना। विधायका को प्रमावित करने हेतु विधायका को पत्रादि या प्रचार-सामग्री मिजवाना। विधायका को प्रमावित करने के लिए अच्ट एव अनुचित तरीको का भी प्रयोग किया जाता है।

ध्यवस्थापिका को किस सीमा तक प्रमावित विया जा सकता है, यह बहुज देश विशेष की शासन प्रणाली पर निमर करता है। व्यवस्थापिका का धार्म प्रणाली में कितना महत्व है? व्यवस्थापिका एव कायप्रालिका तथा नौकरशाहिं के से सम्बाध प्रणाली वाले देशा म प्रमाव-समूहा द्वारा व्यवस्थापिका के अपेक्षा निमम्बण्डल को प्रमावित किया जाता है। लेकिन जिन ससदीय देशा म का पालिका शास्त्रिकाली नहीं होती एव व्यवस्थापिका अपेक्षा निकास की प्रणाली वाले देशा म प्रमाव साम का प्रणाली का समदीय देशा म का पालिका शास्त्रिकाली नहीं होती एव व्यवस्थापिका अपकाल शास्त्रिकाली होती है वह का समदीय स्थापिका को उपेक्षा नहीं कर सकती।

कायपालका व्यवस्थापका का उपक्षा नहीं कर सकती। लेक्नि संयुक्त राज्य अमेरिका जैस देश में जहाँ शक्ति पृथक्करण के सिढा^{त रो} मा यता दी गयी है, व्यवस्थापिका को ही प्रमावित करने का प्रयत्न किया जाता है।

इसके अतिरिक्त जिन देशा में बहुदलीय पद्धति होती है और मिश्रित सरकार बर्गी है वहाँ व्यवस्थापिका का कायपालिका पर अधिक नियायण रहता है। अतः आवस्था पिका को प्रमावित करने के प्रयत्न स्वामाविक हो हैं। जिन व्यवस्थापिकाओं म द्^{तृत} अनुसासन दीला होता है उनके सदस्यों को सरलता से प्रमावित किया जा सकता है। व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रमावित करने के अतिरिक्त समितिया को बी

स्थनस्थापका के वदस्या को प्रभावित करने के अतिरिक्त सागितया का "प्रमावित किया जाता है क्यांकि समितिया विधि तिमाण में महत्वपूरण भूमिका वर्ष करती हैं। कि जिन देवी—असे समुक्त राज्य अमेरिका— सं समितियों की प्रवास के अधिकार होते हैं, यहां उन पर ध्यान के द्वित होना स्वामाविक हैं।

काइनर का मत है कि आज हम प्रमाशों के केद में निवास करते हैं। वनवर्त की कोई उपका नहीं कर सकता। प्रमाशों के बृत्त में होने के कारण नेद्र स्थार्ति कीया नी मनोदशा के अनुरूप बीर स्थानीय क्षेत्र केद्र की मनोदशा ने अनुवार कीयों ती

¹⁸ देखिए अध्याय 13

¹⁹ Finer, H op est p 391

द्विसदनवाद [BICAMERALISM]

व्यवस्थापिका से सम्बच्धित एक महत्वपूष प्रश्न यह है कि उसकी रचना कसी होंनी चाहिए ? व्यवस्थापिका का स्वस्थ क्या हो ? व्यवस्थापिका के दाियत्वी एक कार्यों म धीमता एव सावाबेव को स्थान नहीं हो सकता । अत उसकी रचना ऐसी होती चाहिए जिससे कि उसके कार्यों में अधिक से अधिक सतकता एव विचार-विमय को पूजाइए हो सके । अत अधिकाश आधुनिक व्यवस्थापिकाएँ डिसवनारक हैं अपींत व्यवस्थापिकाओं म दो सदन होते हैं । स्ट्राग के अनुसार अधिक महत्वपूष राज्या की डिसवनारककता एक विवोधता है । माइस ने इस बदक में कहा था कि सबैधानिक इतिहास की किसी शिक्षा का इतना गहरा प्रभाव नहीं हैं जितना कि डितीय सदन के प्रयोग की शिक्षा का है । वह राज्यों में एकसदनीय अध्यक्षाकृत कम पायी जाती है और यदि होती मी है तो वह स्थायी नहीं होती ।

िंदायन की प्रवृत्ति अप्रेशाकृत अधिक हैं। लेकिन इसके अपवाद मी हैं। पूर्णीलण्ड ने 1950 ई एव डेनमाक ने 1954 ई में अपने यहाँ दिलीय सदनों को समाप्त कर दिया है। समुक्त राज्य अमेरिका के 50 राज्या में से केवल नेवरास्का (Nebraska) ने 1937 ई में दिलीय सदन को समाप्त कर दिया था। आस्ट्रेलिया में भनी सलण्ड राज्य में एकसदनीय व्यवस्था है। इसके विपरीत उदाहरण मी पाय जात हैं। 1923 ई में अलातुक कमाल के नेतत्व मंतुकीं मंस्थापित गणराज्य मं एक- सदनीय व्यवस्था की प्रारम्भ में स्थापित गणराज्य मं एक- सदनीय व्यवस्था की प्रारम्भ में स्थापित गणराज्य मं एक- सदनीय व्यवस्था की प्रारम्भ में स्थापित गणराज्य मं एक- सदनीय व्यवस्था की प्रारम्भ में स्थापित गणराज्य मं एक- सदनीय व्यवस्था की प्रारम्भ में स्थापित गणराज्य में एक- सदनीय व्यवस्था नार्वे मा मी है। नार्वे की व्यवस्थापिका (Storting) एक सदन के रूप म निवाचित होती है लेकिन निर्वाचित होने के बाद दो मागा म विमाजित हो जाती है। एक माण नोगटित (Lagting) नहलाता है। इतम 83

Bicameralism is a characteristic of most important States today '-Strong, C F op cut, p 194

सदस्य स्टारिंग (Storting) के सदस्या द्वारा चुने जाते हैं। दूसरा माग आउतरा (Odelsting) कहलाता है जिसम दोप 112 सदस्य होत है । लागटिंग (Lagting) को विधि प्रस्तावित करने की शक्ति प्राप्त नहीं हैं। यह सदन ओडलेस्टाग द्वारा प्रतु विधेयको म केवल सशोधन प्रस्तावित कर सकता है। यदि सशाधन अस्वीहत हिं जाते हैं अथवा लॉगटिंग (Lagting) अपन विचारा पर हड़ है तो दोना सदता है सयुक्त अधिवेशन म दो-तिहाई बहुमत से निणय किया जाता है। द्विसदन की वर्ग करते समय एक श्रम उत्पन्न होने की सम्मावना है। सभी देशा म प्रथम एव डितीय सदन शब्दों का प्रयोग समान अर्थों में नहीं किया जाता है । ब्रिटेन, कनाडा, फार्ड, इटली आदि देशो म प्रथम सदन जनता द्वारा निर्वाचित सदन है। दूसरा सदन दिवीय सदन कहसाता है। अमरिका एव आस्ट्रेलिया म दोना सदन निर्वाचित होते हैं। इन राज्या म प्रथम सदन वह सदन है जो जनसच्या के अनुपात म गठित होते हैं। द्वितीय सदन म प्रत्येक राज्य को समान स्थान प्राप्त होत हैं। भारत का प्रथम सदन-लोकसमा (The House of the People)—जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति सं निर्वाचित सदन है एव द्वितीय सदन (राज्यसमा) जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित सदन है पर तु वह राज्या का प्रतिनिधि सर्दन माना जाता है। भारत म अमेरिका, आस्ट लिया स्विट्जरलैण्ड के उच्च सदना की मौति राज्यो को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है अपितु जनसख्या के अनुपात म हर राज्य को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। रुष राज्यो में — जैसे नीदरलण्ड एवं स्वीडन में — जनता द्वारा निर्वाचित — सदन द्विती सदन एव अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित उच्च सदन प्रथम सदन कहलाता है।

इस अम के निवारणाथ ह्वीयर ने प्रथम एवं दितीय सवत (First ad Second Chamber) के स्थान पर निन्म पुत्र उच्च सदन (Lower and Upps Chamber) के प्रयोग का सफाव दिया है। व

ादया ह*ा* द्विसदनवाद

क्षाद्रभाषाम् । एकद्यवनीय होनी चाहिए अथवा द्विसदनीय, यह एक महत्वनुक्ष । प्राप्त होनी चाहिए अथवा द्विसदनीय, यह एक महत्वनुक्ष । प्राप्त के समय से तीज विवाद का प्रश्त रहा है। दोनों ही प्रश्न । किस के समयका ने अपने अथन पक्ष म सवल एव प्रामाणिक तक उपस्थित कित है। कि पर विचाद कर के पूर्व द्विसदनातमक अयनस्था नी उत्पत्ति म सहायक तत्वों की समीधां वाद्यनीय है। काइनर के अनुसार 'अयवस्थापिकाए दो मुख्य एव पूषक नारणों से दिन दात्तमक है (1) सपयाद, एव (11) सविधाना में सोकप्रिय सिद्धात को सीमित करते की इच्छा । इसका यह अथ नहीं है कि सधीय राज्या में द्वितीय सदन का निर्माण वेवन राज्या को प्रतिनिधित्व प्रतान करने के लिए ही किया गया था । सधीय राज्यों म मी दितीय सदन के निर्माण के पीछ सोकप्रिय या जन सिद्धात वो सीमित करने की इच्छा ना अमान नहीं है।

² Wheare K C op cst, p 133

इन दो कारणों के अतिरिक्त दो अय मूल आकाक्षाओं ने भी दितीय सदन की स्यापना से योग दिया है। प्रथम, हर व्यक्ति सम्मावित भूल से बचने एव अपने को इस सम्ब प में पूण स तुष्ट करने के लिए हर सम्भव परामश्च ले लेना आवश्यक समम्त्रता है। शासन का काय किन्न होता है और उसके मलत कार्यों का सशोधन भी उत्तना ही किन्न है। अत ऐसी सस्याएँ स्थापित की जाती है जिनमें विचार-विमश्च के पश्चात निष्वय किये जा मके। शासन के कार्यों का व्यापक प्रभाव होता है। अत सत्ता के दोषा को कम से कम करने के लिए अधिक से अधिक सम्मावना होती है। ऐसे निज्य सामा य दोषों एव निश्चमा की सहल स्वीकृति की अधिक सम्मावना होती है। ऐसे निज्य सामा य दोषों एव निश्कृत प्रवृत्ति से अधिकाशत्या मुक्त होते है। यह सब वे तक हैं जो किसी समस्या पर अधिक विचार विमश्च पर बल देते हैं। यही तक दितीय सदन के समयन का के क्र-बिचु है।

द्वितीय, सत्ता एव सम्पत्तिशाली व्यक्तियो द्वारा उनकी रक्षा के लिए विशेष प्रयस्त किये जाते हूं। वे हर प्रकार के अवरोधका का निर्माण करते है जिससे कि उनकी सत्ता एव सम्पत्ति सुरक्षित रहे। "सभी द्वितीय सब्दों की स्वापना एव रक्षा का एक-मान कारण उत्कृष्ट विवार-विमाश की निष्यक मावना ही नहीं है अपितु यह भी है कि उत्तके निर्माता विशेषकर विरासत म प्राप्त सम्पत्ति एव स्थिति (status) की सौप समाज से रक्षा के लिए इच्छूक होते हैं।"

इगलैण्ड म हितीय सबन लाडसमा सामाजिक एव ऐतिहासिक शिक्तयों के विकास का परिणाम है। अमेरिकी सीनेट की स्थापना में भी तरकालीन परिस्थितियों ने महत्वपूर्ण योग दिया है। इसकी स्थापना के लिए संबंधाद के अतिरिक्त तरकालीन लोक-तन का अव्यवस्थित एव उपद्रवी रूप भी पर्यान्त रूप से उत्तरदायों है। फिलाडेलिक्या सम्मेलन में मेरीलैण्ड के प्रतिनिधि श्री मेकहेनरी का कथन था कि 'मुख्य सकट हमारे सविधान के लाकत की अधिक का प्रति है। ' अन सीनट लाक-तन के लिक वाने पर वह अन्य अगा का आत्मसात कर तती है।' अन सीनट लाक-तन के विवद एक अवरोध था। फान्स के जातिकारी श्रीलोक्सी (Delolme) एवं मोटेस्च्यू हिसदनीम व्यवस्था के विचार को स्वीकार करने के लिए तथार नहीं थे। इसके वो कारण थे। फेन कारिककारों यह सिद्ध करना चाहते थे कि सप्रभुता जनता म निवास करती है और सभी व्यक्ति सभाव हैं। के व विद्यान टरगोट (Turgot), ऐसी वर्डस (Abbe Sie)-इंट), मध्यू दो मोटमार सी (Mathieu de Montmorency) ने एक सदन का तीय समयन किया है। मैध्य का कपन था कि यदि सीनट पर स्थार की जाती है तो इससे निरस्वत प्र की स्थापना होगी और जनता दासता पर विसार की जाती है तो इससे निरस्वत प्र की स्थापना होगी और जनता दासता पर विसार

All second chambers have been instituted and are maintal not from the disinterested love of mature deliberation because there is something their makers wished to defend the rest of the community, especially inherited possent status."—Finer, H. op. cit., p. 400

यनेगी। फलस्वरूप 1791 ई एव 1793 ई के सिवधाना मि दितीय सदत की स्वाप्त नहीं की गयी थी। 1848 ई नी सिवधान समा ने भी द्विसदनीय व्यवस्था के ब्रस्ती कार कर दिया था। लेकिन 1875 ई म फा स म तुतीय गणराज्य की स्थापना पर सीनेट की स्थापना की गयी थी। यह व्यवस्था वामपाथी अल्ससस्यक दला एव रिष्य पायी य मध्यमपाथी दला के मध्य समाभीते का परिणाम था। ब्रिटिश जपनिया, कता, क्यास्ट्रेलिया, मारत औदि देशा म द्विसदनीय व्यवस्था इंगलण्ड की सबैधानिक व्यवस्था क्षेत्र की सबैधानिक व्यवस्था क्षेत्र की सबैधानिक व्यवस्था क्षेत्र की सबैधानिक व्यवस्था क्षेत्र की सबैधानिक व्यवस्था की सबैधानिक व्यवस्थानिक व्यवस्थानिक विवास की सबैधानिक व्यवस्थानिक व्यवस्थानिक विवास की सबैधानिक विवास की सबैधानिक व्यवस्थानिक विवास की सबैधानिक व्यवस्थानिक विवास की सबैधानिक सबैधानिक विवास की सबैधानिक व्यवस्थानिक विवास की सबैधानिक विवास की सबैधानिक विवास की सबैधानिक व्यवस्थानिक विवास की सबैधानिक विवास की सबैधानिक व्यवस्थानिक व्यवस्थानिक व्यवस्थानिक विवास की सबैधानिक विवास की सब

द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष म निम्न तक दिये जाते हैं

(1) डितीय सदन प्रथम सदन की निरकुराता पर अकुरा तमाता है। बन स्टूअट मिल का यत था कि प्रयम सदन निरकुरा एव अहकारी हो सकता है अर अविमाजित शक्ति के विनाशकारी प्रमाय से मुक्ति के लिए डितीय सदन आवरण्ड है। डितीय सदन का अस्तित्व लॉक एक्टम की इंटिंट म स्वत प्रता की प्रतिमू देता है और अरपाचार से सुरक्षा प्रदान करता है। एकसदनीय व्यवस्था म यहुमत दस निरकुत है। एकसदनीय व्यवस्था म यहुमत दस निरकुत है। सकता है और कायपालिका एव यापपालिका की शक्ति मानित कर सकता है। एकसुतनीय को समाप्त कर सकता है। माइकुक्त करण था कि "दो सदनो की आवस्यकता का आधार यह विद्वास है कि इरम्प्र में ईप्पालु, अरपाचारी एव अपट होन की स्वामाविक प्रवत्ति होती है अत समान वर्ता से पुक्त दूसरे सदन के निर्माण के डारा इन प्रवृत्तियों को रोकने की आवस्यकता है।"

(2) द्वितीय सदन प्रथम सदन द्वारा बीघता एव मार्वावेश से पारित वि यको की भूलो एव किमयो को सलीधित कर उ ह दूर कर देता है। स्मरणीय है हि मली प्रकार सोच विचार कर पारित की गयी विधियों अधिक स्थायी प्रमाणित होंगे हैं। द्वितीय सदन के फलस्वरूप विधेयक के पारित होंने में थोडा सा वित्तन्व अस्ते हो जाता है परनु इससे जनता एव सदन दोनों को ही विधेयक पर पुर्तवचार में अवसर प्राप्त हो जाता है। अब प्रथम सदन के भावावेश एव बीघता पर दिखें सदन एक वास्ति प्रतिव च है। लेकी के अनुतार प्रथम सदन पर "निय त्रण, सलीव एव अवरोधक की इंग्डि से दितीय सदन की आवस्यकता स्थापित करता है और के अनुतार विधि-निमाण से दितीय सदन आवस्यक सन्तुसन स्थापित करता है और संधोधन करने वाले एक श्रेन्ड सदन आवस्यक सन्तुसन स्थापित

प्रभावन करन वाल एक अष्ठ धवन का शुक्का । गंधारा ह । (3) द्वितीय मदन य उन विभिन्न वर्गों एवं द्वितों को प्रतिनिधित्व प्रान्त हैं । जासा व निर्मा वर्गों को प्रथम सदन ये प्रतिनिधित्व पाने से विचित्र रहें जाते हैं । जासाय निर्मा प्रत्यसंक्ष्यक वंग को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है । जुग्वे (Dwgyl) का मत था कि एक श्रेष्ठ व्यवस्थापिका ये एक सदन को जनता का प्रतिनिधित्व करनी

⁵ The necessity of a second chamber to exercise a controlling modifying retarding influence has acquired almost the position of an axiom '--Leeky, quoted by Garner in Political Science and Government, 1951, p 551

चाहिए और दूसरे सदन मे उन विभिन्न समूहो को प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए जिनम कि जनता विमाजित हो ।

- (4) दितीय सदम म ऐसे योग्य व्यक्तिया को मनोनीत करना मी सम्मव होता है जो निर्वाचना के फमट से दूर रहना चाहते हु। ऐसे प्रमुख व्यक्तियो की सवार, बाइस के अनुतार, बतमान समय मे जबकि राजनीतिनो के प्रति जनता का निदयास गिर रहा हो, प्राप्त करना आवस्यक हो गया है। मारत की राज्यसमा मे राष्ट्रपति को ऐसे 12 सदस्यों का नाम निर्देशित करने का अधिकार है जो ज्ञान, विज्ञान, समाज-सेवा बादि के क्षेत्र मे विक्थात हा।
 - (5) इसके अतिरिक्त द्वितीय सदन के अय लाम निम्नलिखित हैं
- (क) दितीय सदन प्रथम सदन के काय मार को हल्का करता है । छोटे एव कम महत्व के विधेयको पर प्राथमिक स्तर पर विचार के पश्चात उन्हें प्रथम सदन के पास विचार हेतु भेजा जा सकता है। इससे प्रयम सदन के काय भारमे कमी आती है।
 - (ल) समात्मक राज्यो मे हितीय सदन घटक इकाइया का प्रतिनिधित्व करता

है एव उनके हितो की रक्षा के लिए एक अनिवाय आवश्यकता है।

- (ग) दितीय सदन के अस्तित्व म कायपालिका को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। गेटिल के अनुसार 'विधानमण्डल के दोनो सदनो द्वारा एक दूसरे को सीमित करने के प्रयासा के कारण कायपालिका को अपेकाकृत अधिक काय करने एवं उत्तर-दायित्व को सम्पादित करने की अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ' यह व्यवस्था काला-तर में सदन के दोनो ही अगो के हित में है।
- (प) ब्राइस दितीय सदन को निरोप ज्ञान के प्रण्डार के रूप के निकसित करने का पक्षपाती था। द्वितीय सदन बुद्धिजीवियों का सदन होता है। 'सीनेट के सदस्यों में प्रमावदाली वकील, प्रतिस्टित जनरत, यायाधीश एव प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ होते हैं। लीडेंडसमा के निचारों का स्तर कॉम स समा की तुलना में श्रेट्ठ एवं जैंचा होता है तथा लॉडसमा के सदस्य अपेक्षाकृत अधिक योग्य, बुद्धिमान एवं प्रतिमा सम्पन्त भी होते हैं।

मेडीसन (Madison) ने सयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट सम्बंधी सबैधा-निक उपचाधा के निर्माण मे मुख्य भाग लिया था। उसकी दृष्टि मे द्वितीय सदन के उद्देश्य निम्नवत हैं

(1) जनता की शासको से रक्षा।

(2) अपने ही चचल व अस्थिर विचारा एव धारणाओ से अपनी (व्यवस्थापिका की) रक्षा करता। अस्थिर विचारो का कारणअपने हिता की सुचना का अमाव या गलत

 ^{6 &#}x27; in checking each other, the two branches of the legislative organ permit to executives a greater degree of freedom of action and of responsibility '-Gettell, R G op at , p 314
 7 Finer, H ob at , p 401

हिटिकोण या अपनी अस्यिरता एव व्यक्तिगत स्वाय हो सकत हैं। अत "एक अवस्य की आवस्यकता होती थी। ऐसा अवरोध प्रवुद्ध परंतु सीमित सदस्या का नितर होना चाहिए। इसमें मावावेश प्रधान प्रथम सदन के प्रवत परामश को रोक्ने गै वाहित हवता भी होनी चाहिए।"

(3) स्वतन्त्रता भी रहा। महीसन की हृटि म स्वतन्त्रता का अप बिक्य का विकास था। उसके अनुसार सिव्यान का निर्माण भी स्वतन्त्रता की रहा के विरु हुआ था। कासीसी विद्वान लाल्सी टोल्लीनडोल (Lally Tallendol) ने कम का उपरोक्त तकों के आधार पर द्वितीय सदन की रचना का समयन किया है। उद्दर्श कपन था कि द्वितीय सदन द्वारा जल्दवाओं एव भावावेद्य म निमित विधिया पर प्रित वाप रखा जा सकता है, एक सदन के वाह्य अससदीय प्रमावा से सीध प्रमावित होंने की कम सम्मावना होती है, सीनट के योग्य एव अनुमवी सदस्या के निणय बुढिमता पूण होते हैं और जनता के असन्तोय का सामना दोना सदना की सपुनत सता अधिक अच्छी तरह कर सकती है। है

सर हेनरी मेन को हुष्टि म सुसगठिन ढितीय सदन अतिरिक्त सुरक्षा (addi tional security) प्रदान करता है । वह प्रतिस्पर्धी निर्धात्तता (rival infallibility)

का प्रतीक नहीं होता। अत दितीय सदन एक अनिवायता है।

एकसदनवाद

18 में सदी के अन्त एव 19 वो सदो के प्रारम्स म कुछ विचारका न एक सदनीय व्यवस्थापिका का समयन किया था। "यह हर्ष्टिकाण इस सिद्धान के प्रमेव का परिणाम था कि राज्य में जनता सम्प्रमु है और उसकी सामाय इच्छा को ही विधियों के रूप में अभिव्यक्त होना चाहिए। अत प्रत्यक्ष रीति से जनता द्वारा निर्वाचित सदन ही राज्य की सप्रमुता का एकमात्र अधिरकात होना चाहिए और उसी के

माध्यम से सामाय इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए।"

एकसबनीय व्यवस्था के गुरुष समयक 1789 ई एव 1848 ई के फ्रेंच नितियों के नेतागण कोनडोरसेट (Condorcet) एव रोवेसपीयर (Robbespiere) आदि थे। 1848 ई म फा सीसी विचारक लामटीन (Lamarune) भी 1789 ई हे टरगोट (Turgot) की मीति एकसदनवाद का योग्यतम समयक था। जीरिका मंबर्ग मिन फ्रेकिंसिन एवं इंग्लण्ड म वे यम भी इसी मत के समयक थे। एकसदनीय व्यवस्था के समयक ने हिसदनवाद की तीन्न निदा की है और वे उसे निरयक मानते हैं। हिं सदनवाद के विपक्ष के तक एकसदनवाद के सम्यक में विश्व के समयक के अपने स्वाप्त के समयक स्वाप्त समयक स्वाप्त स्वाप

 (1) द्वितीय सदन का सिद्धात लोकतात्र के आदश्चों का विरोधी है। प्रवम सदन पर अकुश लगाने का अथ लोकतात्र प्रणाली म अविश्वास एव जनता के प्रति

⁸ Finer, H op cit, p 403 9 Gettell op cit, p 315

निधियो पर नियात्रण स्थापित करना है। यह घारणा लोकतात्र की आधारशिला को ही हिला देती है।

- (2) दितीय सदन प्रतित्रियाचादियो एव अनुदारवादियो का गढ होता है। अतत हाउस ऑफ लॉर्ड स के विरोध का अत करने के लिए लॉडसभा को शक्ति से विचत करना ही पड़ा। स्मरणीय है कि द्वितीय सदन की स्थापना का एक मृहय कारण समाज के सम्पत्तिवान एव सम्मानित व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना था। इसके अतिरिक्त, द्वितीय सदन प्रथम सदन के कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है। द्वितीय सदनी कें द्वारा अत्यन्त उपयोगी समाज सुधारों का तीन्न विरोध किया गया है और इस प्रकार जन क्रान्ति के लिए माग प्रशस्त ही जाता है।
 - (3) द्वितीय सदन के कारण समय एव धन का अपव्यय होता है।
- (4) द्वितीय सदन के अस्तित्व के कारण प्रथम सदन के अनुत्तरदायी ही जाने की अधिक सम्मावना होती है।
- (5) इस तक म भी अधिक बल नहीं है कि दितीय सदन का विधि निर्माण पर सुधारात्मक प्रमाव होता है। आधनिक राज्यों में विधि निर्माण की एक निश्चित प्रणाली है। प्रथम सदन म प्रत्येक विधेयक पर तीन वाचन एवं समिति में विचार होता है। व्यवस्थापिका म विधेयक को प्रस्तृत करने के पूब यह देखा जाता है कि वह दलीय भीति के अनुकुल है या नहीं । अत भूल या मानावेश अथवा जल्दवाजी में विधि के पारित होने के आरोप में कोई सार नहीं है। प्रत्येक वाचन म विषेयक पर गम्भीर वाद विवाद एव विचार विमश होते है। जनता को भी इस दौरान विधेयक पर अपना मत व्यक्त करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हो जाता है। स्पष्ट है कि प्रथम सदन माना-वेश का शिकार नहीं होता है और न जल्दबाजी म ही उसके द्वारा विधि निर्माण होता है। कभी-कभी तो विधेयक को पारित होने मे वर्षों लग जाते है। उदाहरण के लिए, बिटिश ससद म आयरिश स्वत त्रता सम्बाधी विधेयक पर 30 वर्षो तक विचार होता रहा । ब्रिटिश ससद को आस्टेलिया के सविधान को पारित करने मे 20 वप तथा मारत शासन अधिनियम (1935 ई) को पारित करने मे 7 वप लगे थे।

फेंच विचारक एकी सईस (Abbe Sieyes) एकसदनीय व्यवस्था का समयक था। उसका तक था कि "विधि व्यक्तियों की इच्छा है। एक ही विषय पर व्यक्तियों की दो इच्छाएँ नहीं हो सकती। अत जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली ज्यवस्थापिका अनिवासत एक ही होनी चाहिए। जहां पर दो सदन होगे वहाँ अनिवासत सतभेद एवं कलह उत्पन हो जायेंगे और जनता की इच्छा निष्क्रिय हा जायेंगी। 10 'लोकमत ना सही प्रतिनिधित्व केवल प्रथम सदन ही कर सकता है, द्वितीय नहीं। यदि द्वितीय सदन प्रथम सदन से असहमत ह तो दृष्ट है, यदि समथन करता है तो ध्यथ है।' 11 अत प्रत्येक अवस्था मे द्वितीय सदन अनावश्यक है।

¹⁰

Abbe Sieyes quoted by Garner op cit, p 549
'If the two Assemblies agree, the second chamber is unneces-

द्विसदनारमक व्यवस्था द्वारा राज्य की एकता के महत्वपूण सिद्धान्त को निज जिल दे दी जाती है। गानर के अनुसार द्विसदनारमक व्यवस्थापिका अपने ग ही विसक्त होती है। 13 लास्त्री की हिट्ट म यह आवदमक नहीं है कि प्रयम सन्त की अपेक्षा द्वितीय सदन के अपने निजय सही ही हो। "जनता की जटता (Incris) एवं सासन द्वारा व्यापक परिचतना के टालने की प्रवृत्ति म आवद्यक प्रतिच प सदव ज दिखत होते हैं जो खतरनाक हो सकते हैं और यदि प्रतिच प सनामें जात हैं तो वे निहित स्वार्थों के प्रगति विरोधी हर्ष्टिकोण का ही समयन करते हैं।"33

गेटिल का कथन है नि कुछ आधुनिक विद्वाना ने द्विसदनीय व्यवस्था को राज नीतिक विकास मे सत्रमणकालीन व्यवस्था माना है। 13 द्वितीय सदन राज्य मे विचारे एव हितो के विरोध को व्यक्त करता है। जब हितो की एकता स्थापित हो जायेगी तो दो सदनो की कोई आवस्यकता नहीं रहेगी।

क्या द्वितीय सदन आवश्यक हैं ?

अधिकाद्य देशा में द्वितीय सदन की स्थापना उसकी अनिवासता एवं आवार कता का प्रमाण नहीं है। द्वितीय सदन के पक्ष मं दिये गयं तक भी निर्धान्त एवं अकाट्य नहीं हैं। एस एस आयगर की हिस्ट म द्विसदनीय व्यवस्था लोकत न में एक बीती हुई धारणा है। उनके अनुसार लोकत न में सन्देहास्पद विदवास एवं अस्त सक्यकों को सातुष्ट करने की मावना द्विसदनावाद के ही कारण है। जनमत ही अभिव्यक्ति के दो तरीके गयो होने चाहिए? लोकत न को दो मापाजों म क्या बोलवी माहिए? लोकत न को दो मापाजों म क्या बोलवी माहिए? सत्य तो यह है कि द्विसदनीय व्यवस्था दलीय व्यक्तियों की महत्वाकाक्षाओं को सत्यन्त करने का एक साधन है। 15

हितीय सदन के पक्ष म प्रस्तुत सभी तकों की वैधता असिदाध नहीं है। वह तक कि दितीय सदन सघीय व्यवस्था का एक अनिवाय तस्व है, पूणत सत्य नहीं है। यह सोचना भी गलत है कि हितीय सदन सघीय राज्यों के हिता का अनिवायठ प्रतिनिधित्व करेगा। उदाहरण के लिए, अमेरिकी सीनेट प्रतिनिधि सदन से किसी में प्रकार कम राष्ट्रीय या प्रगतिशील नहीं रही है। मैरियट (Marnott) का यह व्यव अतियागिकपूण है कि हिताय सदन सघीय सविधान की रक्षा के लिए प्रथम एवं प्रमावदाली प्रतिभित्त है।

arana magia e i

sary if they disagree, it is obnoxious' —Abbe Sieyes quoted by Finer, p 403

¹² Double chambered legislature was an assembly divided against itself —Garner op cit, p 550

^{13 &#}x27;The necessary checks are always present in the mertia of the mass and the desire of a government to avoid large changes which may be disastrous'—Laski A Grammar of Politics, p 332

¹⁴ Gettell R G op cut pp 316 317

¹⁵ Asırvatham, E Political Theory, (1965) p 401

आधुनिक समय में हिसदनीय व्यवस्था की अपेक्षा एकसदनीय व्यवस्था की तरफ मुकाव है। विगत वय मारत के अनेक राज्या ने हितीय सदन को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव स्वीकार किये थे। हितीय सदन की शक्तियों को भी कम किया गया है। उत्तहरण के लिए, लांडसमा को शक्तिया कम की गयी है। यूनान, वलगारिया, रूमानिया, वनामा, क्यूबेक एव मोबोस्कोशिया (Novoscotla) नामक दी प्रान्ता को छोडकर कनाडा के समस्त प्रान्त, स्वित कंप्टनो एव वंटिन-अमेरिकन सधी म एकारमक व्यवस्थापिक है। लांकी एक-स्वतीय व्यवस्था मा ममक या। उसके अनुसार एक सदन बहु-अमतायुक्त (multi competent) विधानमण्डल है और आधु निक राज्य की आवश्यकताओं की इंग्डिट से अधिक औरठ है। ससदीय प्रणाती है। जिंत राज्य की आवश्यकताओं की इंग्डिट से अधिक औरठ है। ससदीय प्रणाती है। जी तमत एकसदनीय व्यवस्था कही अधिक सुविधाजनक एव प्रमावकारी होती है।

डॉ आर्शीवादम के अनुसार 'इस प्रश्न का कि द्वितीय सदन आवश्यक है या नहीं' कोई एक उत्तर नहीं दिया जा सकता। यह बहुत कुछ देश विशेष की पूनगामी ऐतिहासिक स्थिति पर किपर है। फास एव सपुक्त राज्य अमेरिका की सीनेटो एव इग्लेण्ड के हाउस ऑफ लॉड्स के समाप्त कर देने से इन देशों की व्यवस्था म निस्ते देह कमी आ जायगी। लेकिन कनाडा से यदि सीनेट को हटा दिया जाय तो इससे कोई विशेष हानि नहीं होगी। 18

उच्च सदनो का सगठन

हितीय सदन को ही उच्च सदन की सक्षा दी जाती है। उच्च सदना की एक प्रमुख समस्या उनके सगठन सम्बाधी है। विश्व के प्रमुख देवा के उच्च सदना को सगठन की हुटिस गानर ने निम्म वर्गों भ वर्गोंकृत किया है ¹⁷

(1) पूणतथा या प्रधानत बझानुगत आधार (Hereditary principle) पर सावित उच्च सदन—इस श्रेणी में इगलण्ड का हाउस ऑफ लॉड्स, हगरी का टेवल ऑफ मेगनेट सदन (1926 ई के पूर्व), साझानीय जापान का पीयर सदन (House of Peers) एवं जास्ट्रिया का उच्च सदन जात है। यह सभी सदन प्रधानत वसानुगत जाधार पर सगठित थे।

(2) मनोनीत (Nomnated) सदन—इस प्रकार के उच्च सदमा की सभी या अधिकाश सदस्य कायपालिका द्वारा जीवन अर के लिए या नुख वर्षों के लिए मनोनीत किये जाते हैं। इसके उदाहरणा हैं—इटली की सोनेट एव ननाडा नी सीनट । जापान के पीयर सदन (House of Peers) के नुख सदस्या नो भी मनानीत दिया जाता था। भारत के उच्च सदन—राज्यसमा—के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनानीत विय जाते हैं।

(3) प्रत्यक्ष रीति से जनता द्वारा निर्वाचित सदन-इस प्रकार के पदना क

¹⁶ Asırvatham, E op cat, p 401

¹⁷ Garner op cif, pp 559 560

उदाहरण है—1913 ई के पश्चात की अमरिकी सीनेट एव ब्राजील, आस्ट्रेंतिण, प्जीसैण्ड आदि की सीनेट भी इसी वग म आती हैं।

(4) अत्रत्यक्ष रोति से सावजनिक मताधिकार द्वारा निर्वाचित सदन—श

श्रेणी म फास एव डेनमाक के उच्च सदन आत हैं।

(5) स्थानीय ध्यवस्थापिकाओं या समितियो द्वारा निर्वाचित सदन—इन्हें उदाहरण पुतनाल, दक्षिणो अफीकी सथ एव नीदरलैण्ड के उच्च सदन हैं। बात में राज्यसमा के सदस्य मी अप्रत्यक्ष रीति से राज्यों की विधानसमाओं के सदस्य झार्य ही चुने जाते हैं।

अनेक देशों के उच्च सदनों के सगठन म उपरोक्त उत्तिलिखत दो या तीन तरीकों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, इगलण्ड के हाउंग अंक लाड स म वशानुगत (hereditary) एवं मनीनीत (nominated) दोना ही प्रकार के सदस्य होते हैं। वतमान जापानी सविधान के पूव के साम्रातीय सविधान के पीयर सदन के सदस्य भी वशानुगत एवं मनोनीत दोनों ही प्रकार के होते थे। उत्तमान के उच्च सदस्य भी वशानुगत एवं मनोनीत दोनों ही प्रकार के होते थे। उत्तमान के उच्च सदस्य भी वशानुगत एवं मनोनीत दोनों ही प्रकार के होते थे। उत्तमान के उच्च सदस्य मों वो प्रकार के सदस्य होता है—प्रत्यक्ष रीति से निवाधित प्रवास निवाधित के उच्च सदन—राज्य परिपद (Council of States)—के सदस्या का वहुष्ट्यक के उच्च सदन—राज्य परिपद (Council of States)—के सदस्या का वहुष्ट्यक केण्डना में प्रत्यक्ष रीति है निवाधन होता है। केवल सात केण्डनों म सदस्य केण्डनों के विधानमण्डलों द्वारा चुने जाते हैं।

वसानुगत एवं मनोनयन की रीति से सदस्यों को नियुक्त करने की पढ़िति तीं आलोचना का विषय रही है। इगलैण्ड को छोडकर प्राय सभी यूरोपीय दशों में वसानुगत सदस्यता समाप्त हो चुकी है। इगलण्ड में भी इसका तीव विरोध हुआ है। फलस्वरूप लॉडसमा को शक्ति से विचित कर दिया गया है। मनोनयन की प्रणाती

मी वशानुगत रीति की मांति अलोकता निक है।

गानर के अनुसार आधुनिक समय म उच्च सदन को लोकप्रिय निर्वाचन द्वारा संगठित करने की प्रवित्त सकती है। जनता प्रत्यक्ष रीति से जिस प्रकार निम्न सदनों के लिए प्रतिनिधियों को चुनती है उसी प्रकार उच्च सदन के सदस्या को भी चुना जाना चाहिए क्यों कि यह पढ़ित लोकत न एवं लाकप्रिय उत्तरदायित्व के सिद्धा के अधिक अनुकूत है। वशानुगत एवं मंगोनीत उच्च सदन केवल संग्रीधन करने वाते सवन की दितीय श्रेणी की श्रुमिका निगाता है। प्रत्यक्ष रीति सं निर्वाचित उच्च सदन के सम्बन्ध म यह प्रका उठता है कि क्या वह निम्न सदन का दुग्यमन (duplication) मात्र नहीं है ? दोनों ही सदना के प्रत्यक्ष रीति सं जनता द्वारा निर्वाचित होने पर उनम सत्ता वे लिए प्रतिस्था स्वामाविक है। सीबर (Lieber) के अनुसार यदि शोगों अदनों को एक ही समय में एक ही निर्वाचका द्वारा चुना जाती है तो वे दोना सदन एक ही सदन की दो समितियों होंगे। अत यह आवस्यक है कि दोना सदनों का संगठन मित्र मित्र आधारा पर होना चाहिए। उच्च सदन को

ब्लुट्सती के अनुसार विधेष वर्गों के हितो या राजनीतिक इकाइयो का तथा निम्न सदन को सामूहिक रूप से जनता के हिता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।

सपीय राज्या भ पटक राज्या के विधानमण्डला द्वारा दितीय सदन के सदस्या की निवाचित करन की पद्धित प्रचलित है। 120 वर्षों अर्थात् 1789 ई स 1913 ई तक अमरिकी सीनेट वे सदस्य इसी रीति से चुने जाते थे। तेकिन इस प्रणाली मंभी दोष हैं। 1913 ई म अमेरिका म प्रचलित व्यापक प्रष्टाचार के कारण इसका परित्याग कर दिया गया। वहुपा गया के विधानमण्डल के दोना सदनो म गितरोध उत्पन्न हो जाते य और कमी-कमी तो राज्य विधानमण्डल सीनेट के सदस्यों की चुनने के अपने दायित्व को ही पुरा नहीं करते थे।

जत उच्च सदन पा संगठन किस प्रकार किया आय, यह राजनीति शास्त्र की एक कठिन समस्या है। इस सम्बाध म अभी तक कोई सबसम्मत विचार मा धारणा स्यापित नहीं हुई है। जान स्टुअट मिलने इस सम्बाध म अभी तक कोई सबसम्मत विचार मा धारणा स्यापित नहीं हुई है। जान स्टुअट मिलने इस सम्बाध म यह यत ब्यवत किया था कि एक सदन में माध्यम से लोकमत वी अमिष्यिक होनी चाहिए और इसरे सदन में ब्यक्तिगत योग्यता एव प्रतिमा को, जो जनसंवा हारा प्रमाणित हो चुकी हो, स्यान दिया जाना चाहिए। मिल हितीय सदन का स्वामाजिक नताआ (natural leaders) का सदन मानता था। समाजवादों नेता थी एव धीमती विज्ञत थे। सेकिन उहाने मी यह स्वीकार विया है कि आधुनिक व्यवस्थापिकाओं का काय मार अधिक है अत उनक कार्यों को दो मागो—राजनीतिक एव सामाजिक—में विमाजित कर देना चाहिए और विधानमण्डल के एक आग को राजनीतिक सद और दूसरे की सामाजिक सद उसे अन्यावहारिक मानता था। 18 1918 ई में लॉड आइस ने बॉडसमों के सुधार के दिए एक योजना प्रस्तुत की थी लेकिन उस योजना पर सहानुभूतिनुवक विचार नहीं हला।

गानर का इस सम्बाध से यह मत है कि व्यवस्थापिका यदि द्विसदिगिय है तो धोना सदना को मिन आधार एव सिद्धात पर सम्रिट्ट किया जाना चाहिए । इनमें से एक सदन के सदस्यों का कायकाल वर्षेद्वाकृत लम्बा होना चाहिए । उनकी योग्यता एव कायकाल मी अधिक होना चाहिए तथा उनके निर्वाचन के से से बे होने चाहिए । उनका निर्वाचन के मत्र प्रकार से गठित निर्वाचको एव मिश्र निर्वाचन-प्रमाणी हार होना चाहिए । विकान आधुनिक लोकत नीय मान्यताएँ एव विश्वास ऐसे सदनों के पक्ष मन्दी है । जहा पर उपरोक्त सभी बाते पायी जाती है वहाँ एक सदन आकार में छोटा होता है पर जु उसमें अधिक अनुसवी एव अधिक अवस्था के अनुस्तावादा सरस्य होते हैं और ऐसा सदम सम्मतिशालियों एव बुद्धिवादियों के हितो का प्रतिनिध्यन करता है । अमर की उपरोक्त धारण के अनुस्त्व बनेक देशो—अमेरिका, भारत आदि—

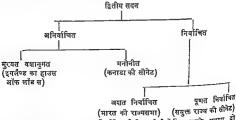
18 Laski Parliamentary Democracy in England, p 337

¹⁹ Garner op cit, pp 565 566

के उच्च सदना का गठन किया गया है। सम्मवत यह सयोग ही है। मारतीय लाइक की तुलना मे राज्यसमा के सदस्यों की सस्या बहुत नम है अयान आधी है। उप्लॉ का कायकाल 6 वर्ष है। राज्यसमा एक स्थायी सदन है। राज्यसमा के सदस्य कमानु पातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर राज्या की विधायिका परिपद के निवा सित सदस्यों हारा चुने जाते हैं। अत लाक्समा की तुलना म राज्यसमा के निर्वाचन क्षेत्र वर्ड हैं, निर्वाचन प्रणाली एवं पढ़ित और निर्वाचनकाण भी निन्न हैं। अमित सीनेट भी एक छोटा सदन है। उसके निर्वाचन के निर्वाचन प्रणाली एवं पढ़ित और निर्वाचनकाण भी निन्न हैं। अमित सीनेट भी एक छोटा सदन है। उसके निर्वाचन क्षेत्र भी वर्ड है। सीनेट एवं राज्यकों की सदस्यता के लिए अधिक आयु सम्बंधी योग्यता की व्यवस्था है। वैत्वियम, प्राक्त पीलेंग्ड एवं हटली में 40 वर्ष की अवस्था पार करने पर ही दितीय सदन के इन्त की सकते हैं। इन देशों के उच्च सदनों म अधिक अनुभवी राजनीतिना को सेवार प्राप्त की आ सकी है।

उच्च सदनो का वर्गीकरण

उपरोक्त सगठन पद्धतियां उच्च सदनो के वर्गोकरण का आधार भी हैं। सकती हैं। सी एक स्ट्राग ने उच्च सदनो को दो प्रमुख वर्गो म विमाजित किया है। प्रयम, अनिर्वाचित (Non Elective), एव द्वितीय, निर्वाचित (Elective)। इन्हें वह दो दो उपमाग करता है। अनिर्वाचित सदन के दो उपमाग हैं—वर्गाहुग्रंत (hereditary), एव मनोनीत (nominated)। निर्वाचित उच्च सदना के भी रे उपनाग हैं—'अश्वत निर्वाचित या 'तूपत निर्वाचित'। स्ट्राग अपने इस वर्गी करण को पूण नहीं मानता है। किसी एक देश के उच्चसदन के सगठन म किसी एक देश के उच्चसदन के सगठन म किसी एक ति चार स्वाचित का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके उपरोक्त वर्गोकरण को हम निर्मत तिविक्त द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं



(भारत का राज्यसमा) (सपुत राज्य का धान्य इगसण्ड का उच्च सदन अनिर्वाधित श्रेणी म तो है लेकिन उसके सदस्य बी वर्गों के हैं—बद्यानुगत एष मनोनीत। कनाश का उच्च सदन —सीनेट—पूरी तरह मनी नीत सदन है। उसके सदस्य गवनर-जनरस के माध्यम से त्राउन द्वारा मनोनीत किंग जाते हैं। फ़ास तथा इटनी के एकारमक राज्या के द्वितीय सदन—सीनेट—निर्वाजित सदन हैं। फ़ास को सीनेट अप्रत्यक्ष रीति से एव इटली के नबीन गणराज्य का द्वितीय सदन प्रत्यक्ष रीति ते निर्वाजित होता है। आस्ट्रेलिया एव समुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट प्रत्यक्ष रीति से निर्वाजित जज्ज सदन है। भारत के द्वितीय सदन राज्यसमा के बहुसिस्यक सदस्य अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाजित होते हैं एव उसके 12 सदस्य राप्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं।

स्ट्राम क निवाचित वग के दो और उपभाग हो सकते हैं—प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष रीति से निवाचित सदन ।

10

व्यवस्थापिका—उच्च सदन [LEGISLATURE—UPPER CHAMBER]

उच्च सदनों के स्वरूप एव प्रकृति का उचित ज्ञान प्राप्त करने के लिए हुई प्रमुख देशों का उच्च सदनों के सगठन, शक्तियां एव कार्यों का पृषक पृषक अध्यवन वाद्यनीय है। अत हम इगलैण्ड की लॉडसमा (House of Lords), समुक्त राज्य बन दिका सी सीनेट (Senate), कनाडा एव आस्ट्रेलिया के द्वितीय सदनो—सीनेट—पृव स्विच्य एक, सोवियत रूस, मारत के द्वितीय या उच्च सदनों की इस अध्याय म

इगलैण्ड की लॉर्डसभा

आधूनिक समय में लॉडसमा (House of Lords) बद्यानुगत आधार पर गठिउ विदव का एकमात्र उच्च या द्वितीय सदन है एव शेष सभी वशानुगत सदनी का अव हो चुका है। इसी कारण लास्की न लॉडसमा को एक अरक्षित कालभ्रम या विरोधा मास की सना दो है। यह विदव का सबसे प्राचीन सदन है। इसके वशानुगत स्वरूप का कारण ऐतिहासिक है।

लॉडसभा का इतिहास

स्ट्राम के अनुवार, 'अधिकाद्य राज्या के वशामुगत उच्च सदन मध्ययुगीन सावन स्ट्राम के अनुवार, 'अधिकाद्य राज्या के वस्त्र प्रमुख सत्य है । तार्द्रसमा के उत्पत्ति दिने के नोमन-नाल की मुख्य सामता एव पादरिया की समिति—महान समिति (Great Counci)—से हुईहै। इसके यथ म तीन अधिवेशन होते थे। 1295 ने माइल पात्रियामस्ट (Model Parliament) के समय राजा एडवड समन ने प्रतक साहर (Shire) से वा सामन एय नगरा, सहरा एव वरा (Boroughs) समुद्ध निर्वा

^{1 &#}x27;For as the second chamber of a political democracy it (House of Lords) is an indefensible anachronism '—Laski H J Palis mintary Dimeriacy in England, 1952, p. 111

चित प्रतिनिधिया को इस महान् सिमिति में और शामिल कर दिया था। कुछ समय तक तो इनके सिम्मिलित अधिवेशन होते रहे लेकिन एडवड तृतीय के शासन-काल मे सामत्ता एव पादित्यो तथा निर्वाचित प्रतिनिधिया के पृथक-पृथक दो सदन बन गये। साम ता एव पादित्यो ते मिलकर लॉडसमा का तथा ग्रामीण एव शहरी क्षेत्रों के प्रतिनिधिया ने कॉम स समा का निर्माण किया। कामवेल के गणत त्रीय काल में लॉडसमा को समात्त कर दिया गया था। 1660 ई में उसकी पुनस्थापना हुई। उस समय सं यह निरक्तर चला आ रहा है।

1832 ई म सुधार विधेयक के पारित होने के परवात बिटेन में नवसुग का सुन्यात हुआ है एवं कॉम स समा का लोकत त्रीयकरण प्रारम्म हुआ ! सुपार विधेयक के प्रश्न पर हुए सथप ने नवीन सामाजिक तस्वों की शक्ति को स्पष्ट कर दिया था ! इस समय में लॉडसमा को पराजित होना पड़ा था ! 1832 ई के सुपार कानून के अन्तात कॉम स समा के लिए जिस निर्वाचन-प्रणाली को स्वीकार किया गया था, उसके फलस्वरूप काइनर के अमुसार लॉडसमा का स्थायी रूप से कामस समा का विरोधी हो जाना एवं निरत्य आस्मरका की स्थित में रहना तथा अन्त में शक्तिहीन हो जाना एवं निरत्य आस्मरका की स्थित में रहना तथा अन्त में शक्तिहीन हो जाना असिवाय था !

18 थी सदी के अत तक काम स समाययाथ म निम्न सदन ही था यद्यपि उस समय भी लाइसमा को कॉम स समा की तुलना म दित्तीय मामलो में श्रेटता प्राप्त थी। दोनो सदनो में मतभेद हुआ करते थे। इन मतभेदी का कारण दोनो सदनो की दितीय शास्त्रियों या राजनीतिज्ञों की विश्वितक महत्याकाक्षाओं में अतर या गुटब दी हुआ करती थी। बीलन पृथक इकाइयों के रूप में दोनो सदनो में कोई मतभेद नहीं थे। 19 वो सदी में कॉम स समा के लोकत श्रीयकरण के साथ सत्ता का के दूर लॉड-सना से हटक र कॉम स समा में अधिकत हो गया था।

लाडसभा का संगठन

लॉडसभा की सदस्य सख्या मे सदैव ही परिवतन होते रहे हैं। इस समय इसकी सदस्य सख्या 1,000 से अधिक है। लेकिन एक व्यवस्था वे कारण यह सख्या घटकर 890 के करीब रह गयी है। साइसभा के उन सदस्या को जो ससद के सभी या सन म उपस्थित होना नहीं चाहते, अनुपरिवत संप्रति वे सिए गायेदन-पश देकर सदन की सदस्यता से हट जाने का अधिकार होता है। सदस्य द्वारा एक माह की पूच-मूचना देने पर अनुपरिवति से मुक्ति की यह व्यवस्था निरस्त हो जाती है।

लॉडसमा में निम्न प्रकार के लॉड स होते हैं

(1) वचातुमत पीयर (Hereditary Peers)—सॉडसमा मे इस वग का बहुमत है। वदा परम्परा से लाड के ज्वेच्छ पुत्र को लाडसमा की सदस्यता प्राप्त होती है। पीयर³ कई स्तर के हाते हैं जैसे डयूक (Duke), मानिवस (Marquis), विसकाजण्ट

² The British Parliament, R 5548/73 B I S (1973) p 7 3 Peer means a nobleman It is a degree of nobility in England

(Viscount) एव बैरन (Baron) । प्रधानमात्री के परामद्य पर राजा द्वारा वधानुग्र पीयरा की नियुक्ति भी की जाती है । इनकी सख्या पर कोई सीमा नही है।

- (2) स्कॉटलण्ड के प्रतिनिधि पीयर (Scottish Representative Peers)— यह भी वशानुगत पीयर ही होत हैं। स्कॉटलण्ड के सभी पीयर प्रत्यक समद के लिए अपने में से 16 सदस्यों को चुनते हैं। 1963 ई से यह व्यवस्था कर दी गयी है कि स्कॉटलण्ड के वतमान सभी पीयर खाँडसभा के अधिवेदाना म माग लेत हैं। इव वा में नये पीयर नही बनाये जा रहे हैं। फलस्वरूप पीयरा का यह बग धीरे धीरे समाव ही रहा है।
- (3) आयरलण्ड के प्रतिनिधि पीयर (Representative Peers of Ireland)— इनकी सख्या 1959 ई म बेचल 1 रह गयी है। ये पीयर भी वशानुगत पीयरो है येणी में ही आते हैं। 1800 ई में 234 आयरिश पीयर थे। सन 1800 ई हैं यूनियन एक्ट के अन्तरात आयरिश पीयरा द्वारा अपन म स 28 पीयरा को लाहस्त्री के लिए निर्वाचित निया जाता था। 1932 ई म आयरलण्ड स्वत् त्र हो गया, फलस्वरूप मबीन आयरिश पीयरो का मनानयन भी बाद हो गया है।

(4) धार्मिक लॉड (Spiritual Lords)—इनकी सख्या 26 है। इस अपी में के टबरी एवं यॉक के आकविदाप, लंदन डरहम एवं विनचेस्टर के विदाप तथा

वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त इयलण्ड के चच के 21 अप विशय होते हैं।

(5) विधि लॉड (Law Lords)—इनकी सस्या नी है। ये प्रसिद्ध विधि वेत्ता होते हैं और जीवन भर के लिए नियुक्त किय जात हैं। इह Lords of Appeal in Ordinary की सज्ञा दी जाती है।

(6) आजीवन लॉड (Life Peers and Peeresses)—जाउन को आजीवन पीयस अधिनियम (1958) के अन्तगत किसी भी रूनी अथवा पुरुष को लाडसभी का सदस्य नियुक्त करने का अधिकार है। ऐसे सदस्य आजीवन लॉड कहनात हैं।

(7) राजवशीय लॉड (Peers of Royal Blood)—लाडसमा मे तीन या चार राजवश के राजकुमार होते हैं। वे दलीय राजनीति से पृथक रहते हैं और लाडसमा के अधिदेशनों में माग नहीं लेते। व

सन् 1961-62 ई म 4 राजवशीय, 854 वशानुगत, \$29 स्कॉटलण्ड एवं 1 आयरलण्ड के तथा 26 आध्यात्मिक, 9 विधि एवं 120 आजीवन लाड थे।

⁴ लॉटसमा के सदस्यों को सुविधा की हृष्टि से दो माना म विमाजित कर सनते हुँ (1) Lords Temporal (सासारिक लाड) एवं (2) Lords Spintual (आध्यारिक लांड)। सासारिक लांड की श्रेणी म (1) इगलण्ड, स्काटलण्ड, मेंट ब्रिटन एवं यूनाइटेड किंगडम के वसानुगत लाड, (2) आजीवन साड, तथा (3) विधि लांड सामिल हैं।

⁵ त्रिटेन क वशानुमत लाखें को उगलैण्ड, ग्रेटब्रिटेन एव यूनाइटेड किमडम के पीयर कहा जाता है। सन 1707 ई के पूर्व जब इमलण्ड, स्कॉटलण्ड एव आयरलण्ड

121

व्यवस्थापिका—उच्च सदन | 259 वसदीय अधिनियम (1911) के पारित होने के पूज लॉडसमा की शक्तिया विद्धा तत कॉम स समा के समक्स थी। लॉडसमा की सक्तिमा निम्मलिक्ति है

विधायो शक्तियां कोई भी विधेयक वॉडसमा की स्वीकृति के विमा विधि नहीं वन सकता। विकिन विधि निर्माण में वॉडसमा की शक्ति कॉम स समा की प्रताम वहुत सीमित है। 1911 ई के सस्तीय अधिनियम हारा लॉडसमा की वाति सीमित कर दी गयी है। गैर विचीय विधेयको को लॉडसमा अधिक से अधिक की वस के लिए रोक सकती है। संसदीय असिनियम 1948 ई हारा इस अविध को पटाकर एक वेप कर दिया गया है। वर्णंडसमा के विचाराथ काम समा की अवेसा विभिन्न विभिन्न प्रस्तुत किये जाते हैं। काँम स समा यथाय में रिजनीतिक सत्ता का केंद्र हैं। किसी समय लॉडसमा को जो शक्तिया प्राप्त थी ने धीरे धीरे उससे निष्क्रमित होकर कॉम स समा को प्राप्त हो गयी हैं।

2 वित्तीय शक्तियां लॉडसमा को वित्तीय मामला में कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। 1614 ६ में लॉडसमा ने कॉम स समा में सवप्रथम वित्त विधेयकों का सवप्रथम इत्तावित किया जाना स्वीकार कर निया था। 1671 ई में कॉम स समा ने लॉड-समा द्वारा करा को कम करने के प्रयत्न का सफल विरोध किया था। उस समय स मह अभिनाम का भारत के अवस्त का चावा विश्व का का का विश्व विभेगको को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। लॉडसमा छह विना सक्षीधित किये हुए स्त्रीकार मा अस्त्रीकार कर सकती है। इस परस्परा को 1909 ई तक मा यता दी जाती रही थी। जोडसमा ने इस अविध में केवल एक विता-विधेयक-माज कर को समाप्त करने वाले विधेयक को 1860 ई में अस्वीकार किया था। 1909 है म लॉडसमा ने कॉम स समा हारा पारित बजट को स्वीकार नहीं किया। र म लाडवभा म काम व वधा द्वारा भारत वजद का स्मामार पट्टा स्थान हो गया। लाडवमा के इस काय का काँम स समा ने तीव मतिवाद करते हुए यह सम्द्र कर दिया था कि लाइसमा को कर-भाग च धमा न ताल प्रांतवाद करत हुए यह स्पष्ट कर १६४१ था भाग पाठवणा भा भरे को छुने का भी अधिकार नहीं है। 1911 ई के संसदीय अधिनियम द्वारा गायसमा का क्ष्म का मा आपकार गहा है। 1911 के क पणवान का नावार कर है। फलस्वरूप ाप्या का विद्यास मामला म साक्त का प्रयत समाप्त कर विद्या र । क्याप्य प्र माइसमा किसी बित्त विधेयक को अधिक से अधिक केवल 14 दिन के लिए रोन सकती है। 3 कामपालक शक्तियाँ —लॉडसमा मं भी शासन की नीतिया पर वाद-

विवाद हीता है एव शासन में प्रका पूछे जात है पर तु उनका उत्तर काँम म समा की प्रवक्त प्रवक्त राज्य थे, जस समय जो पीयर बने थे वे इंगलण्ड के पीयर बहे जाते कर्मनात क्ष पायर कहेंतात है। सन् 1800 ६ क प्रथात जब जाव कार्य के किन्न के से काडम के पीयर क्हनाते हैं।

माति तत्परतापूर्वक नही दिया जाता है। कॉम स की भाति लाडसमा का मित्रमण्ड पर नियात्रण नही है । लाडसभा म मित्रमण्डल के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव के पांखि होने का कोई महत्व नही है क्यांकि ऐसी स्थिति म मित्रमण्डल त्यागपत्र नहीं दता। कायपालिका को नियातित करने की शक्ति लॉडसमा 16वी सदी म ही बी चुकी है। लेकिन लॉडसमा के मदस्य मिनमण्डल के सदस्य होते हैं। 19वी सदी म लाइसना है अनेक सदस्य मित्रमण्डल के सदस्य रहे थे। बाद में उनकी सख्या कम हाती गयी है। लॉडसमा मित्रमण्डलीय मित्रयो का सम्रहालय (Reservoir of Cabinet Ministers) है। विदेश मंत्री अधिकतर लॉडसमासे ही चुना जाता है क्यांकि विदेश दिनाण जिसका सम्बाध गोपनीय बाता से होता है, के प्रशासन का उसे विवरण दने की आवश्यकता ही नहीं पडती । 1937 ई के मन्त्रियो सम्बन्धी अधिनियम में यह व्यवस्य है कि कम के कम मन्त्रिमण्डल के दो उच्च सदस्य लॉडसमा के होने चाहिए। इत्हें अतिरिक्त लॉड प्रेसीडेण्ट (Lord President) या लॉड प्रीवीसील (Lord Privy Seal) या दोनो ही लॉडसमा के ही सदस्य होने चाहिए । सैलिसवरी के मित्रमण्डल में 10, वालफोर के मित्रमण्डल मं 8 एवं 1937 ई मंचेम्बरलैन के मित्रमण्डल मं 6 मंत्री पीयर थे। 1950 ई के श्रमदलीय मित्रमण्डल म 3 केबिनेट मित्री लॉडसमा के सदस्य थे। 1955 ई मे ब्रिटिश केबिनेट के 4 मात्री लॉडसमा के सदस्य थे। 4 "याधिक शक्तिया-लॉडसमा ग्रेट ब्रिटेन का सर्वोच्च पूनरावेदनीय (appd

भ विभावक शास्त्रया—लॉडसभा ग्रेट ब्रिटेन का सर्वोच्च पुनरावेदनीय (विशेष्टी । तिक्षं) यापालय है। जब लॉडसभा का सर्वोच्च पुनरावेदनीय यापालय के इन म अधिवेदान होता है तो अभिसमय के अनुसार केवल नो विधि लाड ही उडिंग भाग लेते है एव लाड चा सलर (Lord Chancellor) अध्यक्षता करता है। साइनों को कॉम स द्वारा लगाये गये महाभियोग की जाच करने का अधिकार है। पर्षे मिनमण्डलीय उत्तरदायित्व के सिद्धात के विकास के कारण लॉडसमा की यह धार्मि महत्वहीन हो गयी है। इस अधिकार का दीघकाल से प्रयोग नहीं किया गया है एवं अतिम महाभियोग 1805 ई म लगाया गया था।

ससदीय अधिनिमय, 1911 ई लाडसमा की शिक्तिया ससदीय अधिनियम 1911 ई के द्वारा अनेक मानती में सीमित कर दी गयी हैं और उसकी शक्तिया का सही अनुमान ससद अधिनिय 1911 ई के लान के बिना अपूण है। 1892 ई से 1895 ई तक उदारदत सर्ग कि पार्ट के स्वत नता विषयक विधेयक (The Home Rule Bill) को कॉम स समा ने पारित किया था लेकिन लाडसमा ने इसे अप्लोइन कर दिया था। इसी समय लॉडसमा के सब्योधन या सुपार का निश्चय उदार दत कर चुका था। 1905 ई म उदार दत पुन सत्ताब्द हुआ। दोना सदना म संपर्य

णरम्म हो गया था जिसने 1909 ई म उपतम रूप यारण कर तिया था। 1909 र यजट म इनक्स टक्स की दर ऊँची कर दी गयी थी, मृत्यु-कर, खाना दर रूपि मृत्य-वर (Land Values Duties) लगाने की व्यवस्था की गरी

थी। इन कर प्रस्तावो का मु-स्वामियो एव सम्पत्तिशालिया पर विपरीत प्रभाव पडना स्वामाविक था। फलत लाडसमा ने वजट को अस्वीकार कर दिया। लॉडसमा ने इस प्रकार उस शक्ति का प्रयोग किया जिसका प्रयोग आधुनिक वजट-प्रणाली की स्यापना के समय से नहीं किया गया था। वित्तीय मामला में हस्तक्षेप करके लॉडसमा ने नॉम स सभा के एकाधिकार पर अपना दावा किया एव मिनमण्डल को चुनौती दी थी। विरोध में कॉम स समा ने एक प्रस्ताव पारित किया था और लॉडसमा के इस काय को सर्विधान मग करने एव सत्ता अपहरण की सज्ञा दी। मित्रमण्डल की माग पर काम स समा को भग कर दिया गया और जनवरी 1910 ई मे नवीन चनाव हए। चुनावों के दौरान उदार दल ने लॉर्डसमा की शक्तियों को कम करने की घोषणा की। उदारदलीय सरकार को नवीन चुनावा म बहमत प्राप्त हुआ । फलस्वरूप लॉडसमा की शक्ति को सीमिल करने के लिए एक विधेयक 1910 ई म प्रस्तुत किया गया। इस बार लॉडसमा ने समपण कर दिया। सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिनियम काम स में पारित होने के पश्चात लॉडसमा में प्रस्तृत किया गया । लॉडसमा में उसके पारित होने की आशा नहीं थी। मित्रमण्डल ने लॉडसमा म उसे पारित करने के लिए अति रिक्त सदस्य नामजद किये जाने (swamping) की माग राजा से की । राजा जॉज पचम ने प्रधानमात्री को जनमत जानने के लिए निर्वाचन का सुभाव दिया। एक सवदलीय सम्मेलन प्रधानमात्री एस्विवय (Asquith) के नतत्व मे सवसम्मत योजना की स्वीकृति के लिए आयोजित भी किया गया था। वह असफल रहा। दिसम्बर 1910 ई मे नवीन निर्वाचन हुए। विवाद का मूर्य विषय लाडसभा का सुधार था। निर्वाचन के फलस्वरूप कॉम स में शक्ति स तुलन अपरिवर्तित रहा अर्थात चुनावो मे उदार दल की विजय हुई। शासन द्वारा यह घोषणा की गयी कि राजा ने लाडसमा के विरोध को निध्किय बनाने के लिए अतिरिक्त पीयरों की नियुक्ति का आखासन दिया है। इस पर लॉर्डसमा भूक गयी और अत म विधेयक पारित हो गया। यही ससदीय अधिनियम 1911 ई कहलाया । इसकी मुख्य भाराएँ निम्नवत है

1 धन विधेयक—(1) धन-विधेयक के कॉम स द्वारा पास्ति किये जाने एव लॉब्समा में प्रम्युत करने के एक माह के परचात यदि बिना किसी सशोधन के पारित गेही किया जाता तो उसे राजा के समक्ष हस्ताक्षरो हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए और हस्ताक्षर होन पर वह ससदीय अधिनियम वन जायेगा । कॉम स समा द्वारा पन विधेयक को लॉब्समा में सजावसान के कम री कम री माह पूच मेजने की अनिवाय व्यवस्था की गारी ।

(2) घन विधेयक से अय उस सावजनिक विधेयक (Public Bills) से हैं जिसका सम्बन्ध स्थीकर की सम्मति म कर. ऋण एवं सावजनिक घन स हो।

इस समय लॉडसमा की सदस्य सख्या 554 थी। 1909 ई के बजट के विपक्ष म 350 एव पक्ष मे 75 मत आये थे। स्पष्ट है कि बहुत बड़ी सख्या म लॉड-समा के सदस्याने माग लिया था।

(3) प्रत्येक धन-विधेयक को लॉडसमा एव काउन के पास नेजे जात समय स्पीकर द्वारा मुद्रित एव प्रमाणित किये जाने की अनिवाय व्यवस्था की गयी अर्थात धन विधेयक के सम्बाध म कॉम स समा के स्पीकर के निषम को अतिम एव भाग ठहराया गया । सक्षेप म, कर एव व्यय सम्बाधी मामला म लॉडसमा के कोई अधिकार नहीं रह गये है।

2 अ.य सावजनिक विघेयक—किसी सावजनिक विघेयक को यदि कामन समा द्वारा अपने निरन्तर होने वाले तीन सन्नो, चाहे वे सन्न एक ही ससद के ही या न हा, म पारित कर दिया जाता है एव लॉडसमा उसे तीसरी बार मी अस्वीकार कर देती है, तो काउन के द्वारा स्वीकृत होने पर उस विधेयक के अधिनियम बन जाने नी व्यवस्था की गयी है। लेकिन इस व्यवस्था में केवल एक रात यह रखी गयी कि विध्यक के प्रथम बार प्रस्तुत करने के द्वितीय बाचन एव तृतीय बार के तृतीय बाचन की तिर्पि म दो वप का अतर अनिवायत होना चाहिए।

इस व्यवस्था के द्वारा लॉडसमा के निरकुश निर्पेधाधिकार (absolute veto) को अस्थायी निवेघाधिकार (suspensive veto) म परिवर्तित कर दियागया है। लॉडसमा गैर वित्तीय विधेयको को इस नवीन व्यवस्था के अ तगत अधिक से अधिक दो वप के लिए किसी विधेयक को रोक सकती थी।

3 ससद का कायकाल 7 वप से घटाकर 5 वप कर दिया गया है। इसकी यह अय है कॉम स समापर लॉडसभाके निय त्रण को कस किया गया है और शीध्र चुनावों की ब्यवस्था के माध्यम से जनता के निय तण म वृद्धि की गयी।

फाइनर के अनुसार इस अधिनियम के निम्न परिणाम हुए है "अनुदारवर्तीय शासन-काल मे लॉडसमा सशोधन की शक्ति का प्रयोग महत्वहीन दिएयो के सम्बध म करती थी लेकिन उदार दल या श्रमदल के सत्ताख्य होने पर इन दला द्वारा सम्पत्ति शाली वग के विरुद्ध जब प्रस्तावित उग्रसामाजिक एव आर्थिक सुधारो को पारित करने का निष्चय किया जाता था तो लॉडसमा अपनी अवशिष्ट शक्ति का प्रयोग करने म नहीं चूक्ती थी।" स्मरणीय है कि उपरोक्त अधिनियम के द्वारा लॉडसमा की गर वित्तीय विधेयको सम्ब घी शक्ति को एक सीमा तक ही सीमित किया था यद्यपि वितीम मामलों में उसे कोई शक्ति नहीं रह गयी थी। गैर वित्तीय मामला में उसे दो वर्ष का निलम्बनकारी निर्वेषाधिकार प्राप्त था जिसके प्रयोग से वह किसी भी विषय^क के मविष्य को सदिग्य बना सकती थी। द्विवर्षीय अवरोध अनिश्चितकालीन अव रोध म परिणित हो सकता था । लायङ जाँज ने लॉडसमा के भूतकालीन आवरण पर टिप्पणी करते हुए कहा या कि "लॉड स सविधान का रक्षक स्वान न होकर अनुदार दर्त के नेता का पिल्ला है।⁷⁸ लॉडसमा के अनुदारदलीय सदस्या मे एव लोकसमा के

⁷ Herman Finer op cit, p 412
8 The Lords would not be the watchdog of the constitution but the conservative leader's poodle -Lloyd George, cited by

उदार विरोधी सदस्यों के बीच गठव घन सरलता से हो जाते थे। उदार दल या मजदूर दल की अल्पसंख्यक सरकार के सत्ताहद होने पर लॉडसमा एसी मरकार की कमजोरी का पूरा लाम उठाती थी। स्पप्ट ह कि अधिनियम द्वारा लॉडनमा की शक्तिया कम तो हुई थी लेकिन इसके बाद भी लाडममा लोकतन्त्रीय इच्छा म बाधा उत्पन्न करन की स्यिति म बनी रही। सास्की न इम सत्य को सही-सही आका था। 1938 ई म लॉडममा के सम्बाध म लास्की ने कहा था कि "ससदीय अधिवियम 1911 ई के द्वारा निर्घारित सीमाओं के वावजूद भी लाडसमा काफी प्रभावशाली है। यह सत्य है कि समदीय अधिनियम के कारण लॉडसमा की स्थिति राज्य म निस्सन्दह घट गयी है लेकिन सामाजिक कारणा स यह सत्ता भी जो स्पष्ट रूप में दिखायी देती है, उसमे कही अधिक है।" लास्की की यह धारणा एवं विश्वाम या कि अमदलीय सरकार के लिए नॉडसमा की यह शक्ति मविष्य मे उमी प्रकार अमहनीय प्रमाणिन होगी जैसे कि 1906 से 1914 तक उदार दल के लिए सिद्ध हुई थी। 1929 31 ई मे अम-दल की अस्पसंख्यक सरकार थी और इस काल में लॉडसमा के आचरण ने उस पयान्त हानि उठानी पड़ी थी। हताश होकर 1934 ई मे थम दल ने लाडसमा के उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया था। ससरीय अधिनियम, 1949 ई

1945 ई में अम दल पुन सत्ताख्व हुआ। इस ममय यह प्रस्न तसने समक्ष या कि लॉडममा का दात्कानिक किमी कारण के और कैस द मुलन किया जाय? 1947 ई के मध्य तक लाडसमा धा त रही लेकिन कीयला खान राष्ट्रीयकरण अधि नियम (1946) एव यातायात अधिनियम (1947) के समय उसने उनका विरोध किया या। अक्टूबर 1947 ई में राजा ने अपने मायण म यकायक लाडसमा की शक्तिया की शिष्क मीमित करने की पोपणा की तथा नवस्वर 1947 ई में मसदीय अधि नियम (1911) को सवीधित करने के लिए अम दल न एक जय अधिनियम प्रस्तुत कर दिया। कुद वर्षों तक इस अधिनियम के फतस्वरूप इसलैण्ड के राजनीतिक जीवन म तहनका सा मचा रहा।

इस अधिनियम के अधीन यह व्यवस्था की गयी है वि लॉडसभा द्वारा किसी गैर-वितीय विधेयक के अस्वीकार किये जान और कॉम स समा द्वारा उस विधेयक को तीन सना के बजाय दो निरतर हान वाले सबा में पारित कर दिया जाता है एव प्रथम बार प्रस्तुत करने के द्वितीय बाचन एवं अन्तिम प्रस्तुनीकरण के अन्तिम वाचन में 2 के स्थान पर 1 वर्ष का ही केवल अनराल हो तो विधेयक पारित माना

^{9 &#}x27;And even after the limitations on that power introduced by the Parliament Act of 1911, its authority remains impressive 'It is true that the Act has reduced the House of Lords to a definitely subordinate position in the State But this is in fact a much greater power than appears on the surface for social reforms'—Lash op et., pp 114 115

जायेगा । दूसरे धब्दा म, लॉडसमा के विलम्बनारी निर्पेषाधिकार की बर्वाध दो वर से घटाकर एक वय कर दी गयी और कॉम स समा मे विधेयक के पारित होने नी प्रक्रियाको भी सरल बनादियागयाथा।

इस विधेयक पर गम्भीर विवाद होता रहा । काम स ने इस विधेयक के पर्स में सबल तक प्रस्तुत किये थे। यथा—सामाय निर्वाचनों में व्यक्त जनमत को प्रथम दिया जाना चाहिए, किसी भी अय लोकत त्रीय देश में ऐसे द्वितीय सदन को स्थान नहीं है जो किसी एक दल का ही समयन करता हो, इगलैण्ड म लॉडसमा के अनुदार दल का समयक होने के कारण व्यवहार म एकसदनीय व्यवस्था की स्थापना हो गयी है, यह निर्विवाद रूप म विलक्षण वात है कि एक ऐसे सदन का व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं जो कॉम स समा की माति निर्वाचित एव विघटित नही किया जा सकता, ससदीय अधिनियम 1911 ई के पारित होने के पश्चात 40 वेप तक अनुदार दल शक्ति में रहा था अत उसे स्वय लॉडसमा का सुधार करना चाहिए था, आदि।

उक्त प्रस्ताव कॉम स द्वारा तो पारित कर दिया गया परातु 9 जून 1948 ई को लॉडसमा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। इसी बीच 1948 म सवदलीय सम्मेलन का आयोजन हा चुका था। उसने लॉडसमा के सुघार सम्ब धी कुछ प्रस्ताव स्वीकार किये थे। लॉडसमा द्वारा विथेयक के अस्वीकार करने पर इन सबदलीय प्रस्तावां की भी अस्वीकृत कर दिया गया तथा प्रस्तावित ससदीय अधिनियम को पारित करने की कायवाही पुन प्रारम्म कर दी गयी। 1949 ई मे इस द्वितीय ससदीय अधिनियम को अतिम स्वीकृति प्राप्त हुई।

लॉडसभा के विरुद्ध तक

लॉडसमा की तीव्र आलीचना की गयी है, जो निम्नवत है

(1) यह प्रतिक्रियावादी सदन है और निष्पक्ष तथा स्वतान विचारधारा बाला सदन नहीं है। लॉडसमा का अनुदारनादी दल की ओर विशेष भूकाव है। सास्की के अनुसार 'जब अनुदार दल की सरकार होती है तब लाडसमा सम्मवत एक अच्छा द्वितीय सदन होता है।" प्रगतिशील सरकार के सत्तारूढ होने पर लॉडसमा के हिंटिकोण के कारण उसके कार्यों में अनेक गतिरोध उत्पन्न होते है। "ऐसे समय लाडसमा अनुदार दल की रक्षित शक्ति के रूप म काय करता है। निर्वाचन में वह प्रगतिशोल वंग की विजय के परिणामा को संशोधित करने के लिए कृतसकल्प रहता है तया अपनी शक्ति भर प्रयत्न करता है।"30 1938 ई मे लॉडसभा की सदस्यता का विदलेषण करते हुए लास्की ने कहा था कि लगमग 750 सदस्या म से 12 पीवर

^{10 &#}x27;The House of Lords, when a Conservative Government is in office is perhaps as good a second chamber as there is in the world It becomes the reserve power of the Conservative Party, determined to correct the consequences of a progressive victory at the polls so far as hes in its power? Laski op al.

श्रमदलीय, 8 उदारदलीय तथा 3 या 4 रैमजे मैंबडोनल्ड के राष्ट्रीय ग्रुप के थे। शेप या तो किसी दल के सदस्य नहीं थे अथवा अनुदार दल के प्रति मक्ति रखते थे।¹¹

(2) रमजे म्योर के अनुसार लॉडियमा सम्पत्ति का गढ (fortress of wealth) है। बडे उद्योगा से सम्बच्धित निहित हिता का सदन पर एकाधिकार है। उद्योगपितया, बडी कम्पनियां के डायरेक्टरा, साम्राज्य निर्माताओ, व्यापारियो, जागीर-दारा ना यह सदन केन्द्र है। लास्की के अनुसार "कोई ऐसा राष्ट्रीय प्रमुख उद्योग नहीं है जिसे लॉडिसमा में पर्योप्त प्रतिनिधित्त प्राप्त नहीं।" 1936 ई म लॉडिसमा में 729 सदस्य थे। इनमें से 119 बीमा कम्पनियां के डायरेक्टर, 74 साहकार, 97 क्को, 64 रेलवे कम्पनियों एवं 49 अहाजरानी-उद्योग कम्पनियों से सम्बन्धित सदस्य थे। स्पष्ट है कि लॉडिसमा समाज के सम्पत्तिशाली वग ना यह है।

(3) यह एक बृहद् सदन है एव अधिकाध सदस्य सदन की बैठका म मान नहीं लेते हैं। बेजहोट (Bagehot) को 19वी सदी म लॉडसमा के उपूलन का तो मय नहीं था पर तु उसके पतन का मय अवश्य था क्यांकि उसके अधिकाश सदस्य अपने कतव्यों की उपेक्षा करते थे। लास्कों के अनुसार "मले ही लॉडसमा में इतने अधिक सदस्य हो लेक्नि व्यवहार में वह सबना ही मित्र सदन है। इसकी बठकां में सामा यत केवल 35 सदस्य ही उपिस्वत रहते हैं।" सर बेनियस (Sir Jennings) के अनुसार लॉडसमा में 80 से अधिक सदस्य उपिस्यत नहीं होते। 1919 ई से 1938 ई तक केवल 13 अवसरो पर लॉडसमा में एक समय म 200 सदस्य उपिस्यत हुए थे। आये सदस्या ने तो सदन में कमी विचार ही व्यक्त नहीं किये थे। 100 ऐसे सदस्य है जिन्होंने कि लॉडसमा की सदस्यता की स्वस्य ही नहीं प्रहण की थी।

(4) शालोचको का मत है कि लॉडममा ने प्रगतिशील विधेयको के माग म वाधा उत्पन्न की है। लॉडसमा ने वर्षों तक विधि निमाण के बारे में विलम्बकारी काय प्रणाली को अपनाया है और उन सरकारा के विधेयको को अस्वीकार किया है जि हुं बहु पस द नहीं करता। रमने स्थोर के शब्दों में "लाडसमा सरीधन एवं विलम्ब-कारी सदन है, और इस काय को भी बहु ठीक प्रकार स सम्पारित नहीं करता है।"

(5) सगठन की हप्टि स लॉडसमा लोकत न में एक विरोधामांस है। लोक-त मात्मक देश म बशानुगत हितीय सदन कस्पनातीत है। सिक्नी एव बेट्सि बम के कपनानुसार "श्रमिक वग का इसमें कोई सदस्य नहीं है और न दुकानवारा, लिपिका एव कपनानुसार को ही कोई प्रतिनिधि है। स्त्रियों का भी कोई प्रतिनिधि नहीं है। लाइसमा के निषय उसकी रचना एव सगठन से प्रमावित हाते हैं। अब तक निर्मित सभी प्रति-निधि सदमों में यह निक्रप्टतम है।"

¹¹ Laski op cit p 113

¹² It became merely a delaying body "-Ramsay Muir How Britain is Governed 1951, p. 186

³³ Sidney and Beattrice Webb A Constitution for the Socialistic Commonwealth of Great Britain, p. 63

फाइनर ने लॉडसमा की प्रकृति (spirit) का तकपूण विवेचन निया है। 19वीं एवं 20वीं सदी में लॉडसमा ने अपने अस्तित्व के भीचित्य म सबन वह वि है। वॉडसमा ने समयानुन् अपने अस्तित्व की यायोचित सिद्ध करने के लिए प्रीनिधि सिद्धात का सहारा लिया है। वॉडसमा के 19वीं सदी म काय आपत्तिजनक थे। कि मी लॉडसमा के समयकों ने यह वावा किया कि वह जनता की रक्षा क्व वह निवंचित प्रतिनिधिया—पॉम स-समा—द्वारा निर्मात अवादनीय विधिया से उनने सद्योधित परिवर्तित एवं अस्बीकृत करके करता हैं। 18वीं सदी की अपनी शब्जा का लॉडसमा ने बवाब में आकर ही परिवर्णा करना की सत्विक मन्तव्या की सत्वी में जनता इतनी जागरूक नहीं थीं कि वह लाडसमा की बात्तिक मन्तव्या की समझ सके और न उस समय तक लोकत न का ही पूण विकास हुआ था। पहीं सम की शक्ति वी और उसने इसका सफलताचुक उपयोग भी किया।" 14

लाडसमा ने 19वी सदी में प्रत्येक उदारवादी प्रस्ताव की या तो सशीधित या अस्वीकार किया था । इसके विपरीत, प्रत्येक अनुदारवादी प्रस्ताव को लाडसमा ने सर लता से पारित कर दिया था। फलस्वरूप स्वय ग्लैडस्टोन को लॉडसमा के विरोध श नेतृत्व करना पडा। लॉडसमा के इस कथन का विरोध किया गया कि वह दे^{ग के} स्यायी मत का प्रतिनिधित्व करता है। लॉडसमा ने क्रपको के हितो की दुलना म जमीदारों की स्थिति की रक्षा की, घामिक एवं राजनीतिकएकता को अस्वीकार किया विश्वविद्यालयों में धम विरोधियों (dissenters) को प्रवेश की अनुमति प्रदान ^{नहीं} की, सैनिक हितो की रक्षा एव निधन बरियो को कानूनी सलाह दिया जाना अस्वीकार किया, आयरलैण्ड के साथ दुव्यवहार हुआ, स्वधासित सस्थाओं के विकास का विरोध किया गया, ससदीय सुधारा को अस्वीकार किया गया एव उनका जग मग हुआ, मानव कल्याण से सम्बच्चित अनेक विधेयक वर्षों तक पारित न हो सके एव प्रथम मालिक दायित्व विधेयक (First Employers Liability Bill) जानवूर्न कर अस्वीकृत किया गया या। लाँडसमा द्वारा अनुचित तरीके अपनाये गये। लक्ष्यी की घोषणा करते हुए उसके द्वारा सत्य सिद्धा ता की कृटिल रीति से हत्या की गयी। लॉडसमा द्वारा यह वहाना किया जाता रहा है कि सन्न के जत म विधेयक पर्याप विलम्य से उसके पास पहुँचते है और उपलब्ध समय मे विधेयका पर उचित विचार विमश सम्मव नही है। फिर भी लॉडसमा द्वारा अनेक असम्मव संशोधन विधेयनों म जोड दिये जाते थे जिससे कि उनके उद्देश्य और उपयोगिता ही समाप्त हो जाती थी। 15 लाडसभा की उपयोगिता

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि साँउसमा की तीव आलोचना अस्वा मादिक नहीं है। 1907 ई म थमदल ने लॉडसमा को समाप्त करने का नारा लगाग या। उदार दल उसके संघोधन का पक्षपादी था। लास्की थमदल के निणय से सह

¹⁴ Finer H op cit, p 409

¹⁵ Finer, H op cut p 410

मत था एव लॉडसमा के उन्मूलन का परापाती था। उसका यत वा कि लोकतन्त्रीय समाज म लाडसमा जैसी अलोकत त्रीय सस्या कायम नहीं रह सक्ती। लाडमभा सम्पत्ति एवं विशेषापिकारों का मूत रूप है। अत उसके कारण सम्पत्तिसानिया एव जनता म मध्य अनियाय है। इसक अतिरिक्त, लोकतत्त्र म जन-विराधी सिक्त का अस्तित्व अमन्मय होता है। अत लॉडसमा के उम्मूलन की माँग अव्यावहारिक नहीं थी।

श्रम दल में द्वारो लॉडसना को समाप्त करने की हढ नीति के अनुपनन के परधान भी लॉडसना आज कायम है। लावचय तो यह है कि कि चार वार सत्ताच्छ होने पर भी श्रम दल लॉडसना को समाप्त नहीं कर सका है। एटली कं श्रमदलीय मिमफड़ को 1949 ई के ससदीय अधिनियम द्वारा मुधार करके ही साताथ कर लेगा पड़ा था। वसानुगत लाधार परापता के उदारदलीय प्रयत्न भी असफत रह है। तिराख पर आधारित सहन ने स्थाना कं उदारदलीय प्रयत्न भी असफत रह है। लॉडममा क रूप म मोई परिवतन नहीं हुआ है। उसका लोकत श्रीयरण नहीं हो स्वा है। इसके अस्तित्व का चया कारण है? सामाय्यत लॉडममा के वायम उहने के निम्न कारण दियं जाते है

(1) निटिया जनता का ऐतिहासिक एव प्राचीन सस्याओं के प्रति विदोष अनु-राग एव लगाव है। निटिश सविधान विकास का परिणाम है एव आवश्यकता के अनु-सार उससे सद्याधन किया जाता रहा है। यह वाल वाडकमा पर भी लागू होती है। निटिया जनता के पुरातन प्रेमी होने के नारण आमूलचूल परिवर्तन उस स्वीकाय नहीं हैं। हवट मौरीमन ना मत है कि लॉडसभा का विवेकहीन (urational) संगठन एव उसने प्राचीनना आविनक निटिया लोकतन्त्र के लिए सुरक्षा व्यवस्था है।

(2) लॉडसभा उपयोगी सावजितक होना करती है। यह सहीधन करते वाला (revisory) सदत है। वह कॉम स द्वारा पारित विभेयको को पूरी तरह अस्वीकार तो नहीं कर सकता पर तु उन्हें पहले दो यथ के लिए अब 1 वप के लिए ऐक अवस्य सकता है। इस यीच म जनता को विभेयक के सम्बन्ध में अली प्रकार विचार विमश करने का अयसर मिल जाता है।

(3) यह सदन मावनाओं के श्रीमव्यक्ति स्थल (ventilating ground) के रूप म काय करता है। विभिन्न विषेयकों पर विचार विभय के द्वारा लाइसमा सम्बन्धित विषया पर जनमल का निर्माण करता है तथा शासन को न्रमाधित करने भ योग देता है। लाइममा म बाद विवादों का स्नार अरोसाकृत ऊँचा होता है। इस सदन म अशासन की निर्मक्षता एवं निअयतापूबक श्रासाचना की जाती है एवं उसका कॉम समा पर भी अमाव पडता है जिसके एक्सकप्प गासन अपनी भूता के प्रति मचेत एवं सन्मा एहंता है। लाइसमा का नेता मिन्नव्यक्त ना सदस्य होता है और उसका यह क्तव्य है कि वह मन्त्रिमण्डल को सदन की मावनाओं से अवशत कराता रहे।

(4) लोकतान्त्र में द्वितीय सदन की आवस्यकता को अनुसव किया गया है । ऐसी स्पिति म यदि लॉडसमा को समान्त कर दिया जाय तो प्रस्त यह है कि जसका नया विकल्प होना चाहिए? यदि उच्च सदन का समठन निम्न सदन भी माति है होता है तो उच्च सदन का कोई महत्व व मूल्य नहीं है। एक अप प्रस्न यह में है कि नवीन सदन के समठन वा आधार क्या होना चाहिए। क्या यह मनोनीत होना चाहिए वा नविंचित । जॉर्डयमा सम्य घो यह यब व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं। सिडनी सा के अनुसार एक दल द्वारा शासन चलाना सवैधानिक दौतानियत (constitutional monstrosity) है। इम्प्लिंग्ड म अमेरिकी सीनेट की तरह शक्तिश्वाली एव कास भे पणत न परिपद (Council of Republic) जैसी दुवल एव सम्मानहीन सत्या वस्य हो अन्यावहारिक होनी अत उसको जनता स्वीकार नहीं करेगी। एक हिट्टिमा पर भी है कि नवीन एव अपरिचित सस्या के स्थान पर पुरानी एव परिचित सस्या कोरी क्यों न रखा जाय? वतमान म लॉडसमा की शक्ति को अनेक योजनाएँ प्रस्तावित की गयी हैं सिकन उनम से कोई भी स्वीकार मही सक्षा कर समय के अनेक योजनाएँ प्रस्तावित की गयी हैं सिकन उनम से कोई भी स्वीकार मही सक्षा के हैं। आजकल अम दल के केवल कुछ उम्र सदस्य ही लाडसमा के उम्मत्व समयम करते हैं।

(5) राज्य-काय मे वृद्धि के कारण विधान (legislation) मे भी वृद्धि हुई है। लॉडेसमा की समाप्ति से कॉम स समा के काय का दूना हो जाना स्वामाविक है। ब्राइस ने यह सुफाव दिया था कि विवादहीन विधेयको को पहले लॉडसमा म प्रस्तावि किया जाना चाहिए एव उसके द्वारा पारित किये जाने के परचात उन्हें कॉम स समा सरलता से पारित कर सकेगी। वैयक्तिक विधेयका पर सवप्रथम लॉडसमा म ही विचार किया जाता है। इससे कॉम स का कायमार भी कम हा जाता है।

ब्राइस ने लाडसमा की निम्नलिखित चार उपयोगिताओं का उल्लेख किया है

(अ) लॉडसमा कॉम स द्वारा पारित विषेयको का परीक्षण एव पुनिवार तथा संशोधन करती है।

(आ) निर्विवाद एव वैयक्तिक विधेयको पर लॉडसमा मे सवप्रथम वि^{चार} करके कॉमस के समय की वचत की जाती है।

(इ) विलम्ब का वधानिक महत्व है। लॉडसमा के विरोध के फलस्वरूप विवाद

स्पद विषेयक पर जनमत को समिठत होने का अवसर प्राप्त होता है। (ई) लॉडसमा म पूण एवं मुक्त बाद विवाद के लिए अपेक्साइत अधिक सुलवसर हाता है।

लॉडसभा के सुघार की योजनाएँ

जोडसमा के मुचार के प्रयत्न 19वी सदी म ही प्रारम्म हो गये थे। इस सदी की कोंमस के सुधार की योजनाओं का लॉडसमा द्वारा विरोध किया गया था। सांड समा के नेताओं ने इस प्रयत्न में अपना पतन देखा था। लॉडसमा अपनी रक्षा अपने आपरण को सुधार कर ही कर सकती थी और इसके लिए उसका प्रतिनिधित्वपृष्ट होना आवस्यक था। अत सुधार के प्रयत्न प्रारम्म हुए थे। प्रतिनिधित्व के विद्वार

को इन मुपारा के आधार के रूप में स्वीकार करके बशानु नता को शासनाधिकार के आधार क रूप में अस्वीकार कर दिया गया था।

प्रमुख मुघार-योजनाएँ निम्नानित हैं

- (1) मुपार पोजना सम्ब भी प्रयम विश्वयक तोंड रनेल (Lord Russell) न 1869 ई स प्रस्तुन निया था। इनके अनुमार काउन को प्रति वथ 4 आयीवन पीयर 6 वर्गो से ने नाम रह करने का प्रश्विन रिया था। धा जिनकी कुल सक्या 85 से कम नहीं हानी बाहिए थी। प्रस्तावित 6 वर्ग थे स्कॉटलेश्ड एव आयरलंग्ड के अप्रति-तिषि पीयम, व व्यक्ति जो 10 वथ तक कॉमन्स के नदस्य रह चुके हा सेना एव नी-सना के जिपकारों न्यायाधीग्र एव उच्च विधिक अधिकारी माहित्य विनान एव कना के क्षेत्र म न्यातिनामा व्यक्ति, 5 वर्ष तक आवकारी सोहत्य विनान एव इना के क्षेत्र म न्यातिनामा व्यक्ति, 5 वर्ष तक आवकारी की सेवा करने वाले व्यक्ति। इस प्रस्ताव को Black Sheep Bill की सना दी य्यी और इसे अस्वीकार कर दिया गया।
- (2) 1874 ई न लाड रोजवेरी (Lord Rosebury) एव 1888 ई म लॉड रानवेरी व लाड मैनिसवरी न योजनाएँ प्रस्तुत की थीं। इनम यह प्रकारित किया ग्या था कि नाहनमा की मदस्य-मध्या को कम कर दिया आये तथा लॉडेंगमा के सदस्या द्वारा ही अपन सदस्यों को चुना जाय। आजीवन लॉड स की सख्या 50 निश्चिम की ग्यों दी। इनम से प्रति वय 5 महस्या का चुनने की योजना थी।

1907 ई तक मुधार नी अप कोई चचा नहीं चुनी गयी। इन काल में मुद्रार दन का प्रामन था। 1907 ई म लॉक्समा ने विधि-निनार के सम्बन्ध म सदन नो मुख्य दन के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति ने अपन पित्रदन म सदन ने पिए नवीन सविधान का सुख्य दिया दिवा स्वत्र राजवरा के न्याधिक य दार्गित नो की की स्वत्र प्राप्त के स्वाधिक का सुख्य दिया दिवा स्वत्र प्राप्त के स्वाधिक य दार्गित नो की स्वत्र स्वत्र प्राप्त के स्वाधिक य दार्गित स्वत्र स्वत्र प्राप्त स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्य स

1909 ई म लाइ सतहाउन (Lord Lansdowne) न एक सुधार-यावना प्रमुत नी । इम याजना के जनुवार साहहमा की तहस्य-सक्या 330 निरिचन की गर्मी थी । यह याजना नी जस्तीकार कर दी गयी ।

महम मुनार योजना (1918 ई)—1917 ई म सॉड बाइन को अध्यक्षता म साडमना ने मुधार क लिए 30 सदस्तीय समिति गठित की गर्नी यो । इसन अपना प्रनिवदन 1918 ई म प्रन्तुत किया या। इसकी मुख्य विद्यारियों निम्बवन् यो

(1) नार्टममा नी कुल मदस्त-सन्त्रा घटा कर 327 कर दने का नुस्मव दिया गया। तीत-सीवाई सदस्या की समानुषातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर क के सदस्या द्वारा चुन जान का सुस्त्रव दिया गया था। वह सदस्य 13 प्रादे। निवाचित्र किन जान था। ग्रेय सदस्या का दोनो सदना की समुक्त स्थायों पोषरा म न चुन जान की व्यवस्था थी। सदन का कावकाल 12 वर्ष गया जिनम से एक तिहाई सदस्यों के प्रति चार वय परचात पदमुक्त होने की व्यवस्थ थी। इस प्रकार लॉडसमा को एक स्थायी सदन बनाया गया था।

यादस सम्मेलन लॉडसमा के सुधार की हृष्टि से बहुत ही विद्वतापूत्र प्र सजग गवेपणात्मक प्रयत्न था। लेकिन इसके समक्ष दो कठिनाइयाँ थीं विनक सम धान कठिन थे। प्रथम, लॉडसमा के लिए जो शक्तियाँ प्रस्तावित की गयों पी व प्रगतिवादियों की हृष्टि से बहुत अधिक थी और अनुदारवादियों के अनुसार कम थी। दितीय, प्रस्तावित अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कष्टसाध्य थी। साथ ही वह प्रगतिवादियों की हृष्टि में पर्योक्त अलोकतानीय एव अनुदारवादियों के अनुसार कुलीनत नीय नहीं थी। अत उपरोक्त प्रतिवेदन विरोधी विचारों के मध्य समभीते का परिणाम था बी किसी को भी सन्तुष्ट कर सकता।

मिनमण्डलीय समिति प्रस्ताव (1922 ई)—1922 ई म मिनमण्डल हो एक उप समिति ने सुधार की निम्न योजना प्रस्तुत की थी

लॉडसमा में राजबरा को लॉडों, लॉड पादिरियो एव विधि लॉडों के अतिरिक्त प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रीति से लॉडसमा के बाहुर से निर्वाचित लॉड, लॉड समुदाय द्वार लॉडसमा में से ही निर्वाचित सदस्य एवं सम्राट द्वारा नामजद सदस्यों की व्यवस्य की गयी थी। कुल सदस्य सख्या 350 निश्चित की गयी। नवीन प्रकार के सदस्यों की क्यायकाल विधि द्वारा निर्वादित किये जाने की व्यवस्या थी। उनके पुन निर्वाचन को सी विधान था। ससदीय अधिनियम 1911 ई के अनुरूष ही अधिकार वनाये रखने की व्यवस्था थी। मिनम्पडल के बदल जाने के कारण यह योजना नियाचित न हो सकी।

दिसम्बर 1933 ई मे एक अन्य सुघार विषेयक लॉडसमा मे प्रस्तुत किया गया जिसके अमुसार लॉडसमा की शक्तियों मे पर्याप्त बिद्ध करने का प्रस्ताव किया गया था। वित्त विषेयक की ब्यास्या का अधिकार दोनो सदना की सपुक्त सिर्मित की प्रवान किया गया। इसके अध्यक्ष—स्पीकर—की तियुक्त करने का विधान किया गया। सदन की कुल सदस्य सस्या 300 निर्धारित की गयी। 150 सदस्य पीयरो द्वारा एव दोन 150 सदस्यों को ससद के दोनो सदनों के द्वारा प्रस्ताबित रीति म निर्धानित कियों जाने का प्रस्ताबित रीति म निर्धानित कियों जाने का प्रस्ताव था। इस सुधार योजना पर प्रथम दो बाचन पारित होंने के बाद अनुदार दल के नेता बाडबिन के निर्देश पर विचार स्थित कर दिया गया था।

सवदलीय सम्मेलन (1949) के प्रस्ताव—1949 ई म ससदीय अधिनियम 1911 ई का जब सखीधन प्रस्ताव विचाराधीन या अब अनुदार दल के अनुरोध पर लॉडसमा के सुपार की समस्या पर विचार करने हेतु एक सवदलीय सम्मलन का आयोजन किया गया था। लॉडसमा के समठन के सम्बाध म इस सम्मेलन म निम्न सयसम्मत निश्चय किये गुग थे

(1) वतमान बदाानुगत सदस्यता का अंत कर दिया जाय ।

(2) इसके स्थान पर व्यक्तिगत प्रतिष्ठा एव सावजनिक सवा के आधार पर

वधानुगत लॉर्डों मे से संसदीय लॉर्डों की नियुक्ति की जाय । सभी संसदीय लॉर्डा को कॉम स समा के सदस्यों की याति वेतन प्राप्त हो एव उनका आजीवन कायकाल हो ।

(3) स्त्रियो को भी लॉडसभा के सदस्य होने का अधिकार दिये जायें।

(4) ससदीय लॉडॉ मे कुछ राजवशीय एवं पादरी लाड भी होने चाहिए।

(5) जो बशानुमत लाड ससदीय लॉड न बनाये जाये, उहे नॉम स समा के निर्वाचन में मत देने एवं सदस्यता के लिए निर्वाचित होने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

लेकिन इस सम्मेलन के सदस्यों में लॉडसमा की श्राक्तिया के सम्बाध में मतैक्य न हो सका। फलस्वरूप सगठन सम्बन्धी उपरोक्त सवसम्मत रूप म स्वीकृत निणय मी कियाबित न हो सके। समदीध अधिनियम 1949 ई के द्वारा लॉडसमा की निलम्बकारी बक्तियों को और अधिक सीमित कर दिया गया। परंतु मॉडसमा का संगठन सम्बन्धी प्रकृत विवादास्पद बना रहा। 1951 ई में अनुदार दल ने यह वचन दिया था। कि सत्ताक्ष्ठ होने पर वे लॉडसमा के सुदार के प्रकृत का समाधान करेंगे।

1952 ई मे लॉड साइमन (Lord Simon) ने एक प्रस्ताव द्वारा यह सुभाव दिया था कि सम्राट द्वारा प्रति वय 10 आजीवन लॉड नियुक्त किये जाये। लेकिन सरकार ने इस प्रस्ताव को यह कह कर अस्त्रीकृत कर दिया कि वह लाडसमा के सामाय सुधारों की योजना बना रही है।

1952 ई मे चर्चिल ने दूसरा सनदलीय सम्मेलन बुलाने का प्रस्तान किया

था परतु श्रमदल ने इसमे माग लेने से इकार कर दिया।

माथ 1955 है से बाईकाउण्ट सेमुअल ने लॉडसमा मे 1948 है के सम्मेलन के आबार पर सुधार योजना प्रस्ताबित की। 1956 है मे अनुदार दल ने पुन लॉड समा के सुधार सम्बन्धी विचार अपक्त किये। अक्टूबर 1957 है म सरकार ने सुधार समा के सुधार सम्बन्धी विचार अपक्त किये। अक्टूबर 1957 है म सरकार ने सुधारों का प्रस्ताब किया। इसके अनुसार सीमित सख्या मे आजीवन साई की नियुक्ति करने, महिलाओं को लाडसमा का सदस्य बनाने एवं सभी लॉडों को पारिश्रमिक देने के प्रस्ताव किये गये। इन प्रस्ताबों में लॉडसमा की बाक्तिया सम्बन्धी कोई उल्लेख नहीं था। अत इस सुधार योजना में किसी को विश्रेष एचि नहीं थी।

जीवनवयन्त पीयरेज अधिनियम¹⁶ (1958 ई)—इस अधिनियम द्वारा (1) लॉडसमा में कुछ सीमिल सस्या में जीवन बर के लिए—जीवनपर्यन्त सदस्यता (Life Peerage) प्रदान की गयी है, (2) महिलाजों को लॉडसमा की सदस्यता प्रदान की गयी है एवं (3) लॉडसमा के सदस्यों को कुछ दैनिक सत्ता प्रदान किया गया है। इस अधि-निमय के अधीन जून 1958 ई में 14 जाजीवन सदस्य नियुक्त किये गये। इतम बार महिलाएँ थी। 1964 ई में आजीवन सदस्यों की संख्या 7 महिलाओं सहित 45 थी।

¹⁶ The British Parliament, R 5448/73, p 5

इस व्यवस्या का एकमात्र उद्देश्य समाज के विभिन्न क्षेत्रो के प्रतिष्ठित एवं बहुनता व्यक्तियों को लॉडसमा में स्थान देना है। शासन द्वारा यह भी आइवासन दिया गण प कि आजीवन सदस्या की नियुक्ति करते समय विरोधी दल की स्वीकृति भी न ही जायेगी या उदार दल के नेता से परामदा किया जायगा।

पीयरेज अधिनियम (1963 ई)—लॉडसमा के सुमार के पुन प्रवल 1962 ई म प्रारम्भ किय गय। फलस्वरूप 1963 ई म पीयरेज अधिनियम प्रारत हुआ। इस अधिनियम क अलगंत निम्म स्थवस्थाएँ की गयी (1) पतक तार स्थापनी को केवल अपने जीवन मर के लिए लॉडसमा की सदस्यता से त्यापपत्र को अधिकार प्रदान किया गया। त्यापपत्र दने वाले लॉड का उत्तराधिकारी सन्स्था के अधिकार से विल्त नहीं होता है। वह लॉडसमा का सदस्य स्वत वन जाता है।

(2) स्कॉटलैण्ड के सभी लॉड लॉडसमा के सदस्य बना दियं गर्य।

(3) आयरलैण्ड के लॉड सदस्यों को कॉमन्स समा के लिए निर्वाचन का अधि कार दिया गया।

(4) महिना लॉडॉ का भी यह समस्त अधिकार प्रदान किये गय।

पैतक लॉडों को लाडसमा से अपने जीवन सर के लिए परिस्थाग की व्यवस्था एक विशेष कारण से करनी पढ़ी थी। प्रत्येक लॉड की अपनी मरमु के परवात उत्तरी पढ़े थी। प्रत्येक लॉड की अपनी मरमु के परवात उत्तरी उपेष्ट पुन वशानुक्रम के सिद्धान के अनुसार स्वत ही लॉडसमा की सदस्वता हा अधिकारी हो जाता था। प्रधानम श्री मैकमिलन के बाद लॉड होम को अनुसार करे उनका उत्तरिकारी चुना था। लॉडसमा की सदस्यता उनके प्रधानमां ही होने के मार्ग मां बाथा थी क्योंकि परम्परा के अनुसार प्रधानमां की कांग ससमा का ही सदस्य होनी माहिए। उपरोक्त उत्तरिकारी चारोप अधिनियम (1963 ई) के अन्तरात ही लाड होने के सार्व स्वतं सा की सदस्यता से त्यागपन दिया एवं तरप्रचात प्रधानमां श्री का पर ग्रहर्ग किया।

1968 ई म एक बार फिर लॉडसमा के अधिकारा को कम करने की बाठ उठी। दक्षिणी रोडेक्सिया के विरुद्ध कॉम स सभा द्वारा आर्थिक प्रतिव घो विषयक पार्टित प्रस्ताय का माग लॉडसमा ने अवस्द्ध कर दिया था। प्रधानमा नी विस्तान (Wilson) ने सिसमा के इस काय की लोकत न एव सविधान की घारणा के विसक्तुल विप्^{रोह} बताया था।

निष्कप—साँडसभा बवानुमत, रूढिवादी, अनुदारवादी एव पसपाती सदत है तया असाधारण रूप से बहुद है। यह अलोकता िनक भी है। यह किसी का भी प्रति निधित्व नहीं करता। उसे 'जीवित यदास्वी व्यक्तिया का बेस्टमिनिस्टर स्थित गिरवार्य (Westminister Abbey of living celebrities) की सना दी जाती है। काइनर से अनुसार 'यह एक नाश्ययजनक सत्य है कि ब्रिटेन विधिवत, अद लोनत त्रीय सर्ग द्वारा शासित है बयाकि साँडसभा का अस्तित्व बहुमत शासव के सिद्धान्त के ठीक विपरीत है। दो बातें और उल्लेखनीय हैं—(1) लॉडसभा प्रवासकोय एव विदानीति से सम्याधित नीतियों पर भी वाद-विवाद या विचार-विमश्च करती है। यह किसी तरह नी उचित नहीं है कि अलोकत त्रीय सदन के अनुत्तरदायी एव प्रतिनिधित्व-हीन विचारा को विधिक मान्यता-युक्त अधिकार प्राप्त हो ।" (2) लॉडसमा को कॉमन्स समा की मौति ही उन नियमा एव उपनियमा को अस्वीकार करने का अधिकार है जो किसी ससदीय अधिनियम के अधीन निर्मित किये गये हो। यह शक्ति पर्याप्त महत्वपूण है। 7

ससदीय अधिनियम 1911 ई एव 1949 ई के द्वारा लाडसमा की शक्ति को पयाप्त कम करन के पश्चात भी उसके सुधार की माग कायम है। अमदल प्रवल बहुमत स पदारूद होने के वावजूद भी उसका उ मूलन नहीं कर सका। इसका क्या कारण है । यह कहा जाता है कि लाडसमा की वतमान शक्तिहीनता ही उसकी प्रधान शक्ति है। इस कथन म विरोधामास होते हुए भी पर्याप्त सत्य है। अब लाडसमा मे शासन को चुनौती देने की शक्ति नहीं है, अत उसके प्रति उतना तीव अस तोप भी नहीं है।

इसके अतिरिक्त, लॉडसमा का सगठन विदेशियों को विचित्र मले ही लगे पर तु स्वय प्रिटेन-बासी उसकी चितित या ज्या नहीं है। हरबढ मौरीसन का कथन है कि हम द्रिटन वासियों म स्वत नता विरोधी सस्थाओं से काय चलाने की पर्योप्त समता है। किसी चीज स जब तक काम चलता है तब तक उसे वे अच्छा ही सममते हैं या उसके प्रति कम स कम सहिष्णुता का भाव तो रखते ही है। श्रमदलीय सरकार भी अव लॉडसमा म विदेकी एवं लोकत नीम मुधारा के लिए चितित नहीं है। ऐसे सुधारा से लॉडसमा की शक्ति बढ जाने एवं उसके कॉम स समा का प्रतिद्ध दी ही जाने का भम है। हम सपुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट की माति शक्तिशाली द्वितीय सदन नहीं चाहते, यदमान लॉडसमा का तकहीन एवं विचित्र सगठन हमारे ब्रिटिश लोकत म का रखक है।

लाँडसमा के सुपार म उपरोक्त हृष्टिकोण के अतिरिक्त अ य मुर्य बाधा उसके सगठन से सम्बध्ित है। उसका सशीधित रूप कैसा हो और उसके अधिकार क्या हा ? वतमान लाँडसमा के कुछ कतब्य ऐसे है जा दितीय सदन द्वारा सम्पाधित नहीं किय जाते, जस— यायिक काय। व किस सस्था को सीपे जाये ? उपरोक्त किताइयो के वावजूद भी यह सबमा य एव सुनिश्चित मत है कि लाडसमा के अलोकतन्त्रीय स्वरूप को सम्पाद कर दिया जाना चाहिए। लाँडसमा के सुधार के सम्ब प मे निम्न वाता स प्राय समी सहमत है

(1) लॉडसमा लाकत श्रीय मावना के अनुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित सदन होना चाहिए तथा उसका बतमान बसानुगत स्वरूप समाप्त किया जाना चाहिए।

¹⁷ Finer H op cit, pp 416 417 18 Herbert Morrison Government and Parliament, p 194

(2) लॉडसमा को कॉम स समा की तुलना मे द्वितीय स्थान होना चाहिए। उसमे किसी स्थायी दल का बहुमत मी नही होना चाहिए।

(3) उसके यायिक काय समाप्त कर देने चाहिए एव स्वतान यायालय नी स्थापना की जानी चाहिए।

(4) लॉडसमा के दायित्व एक आदय द्वितीय सदन के अनुरूप होने पाहिए।
एसा प्रतीत होता है कि लॉडसमा का बतमान रूप काफी समय तक बर्ग
रहेगा। लास्की की यह सम्मावना भी उतनी ही सत्य वनी हुई है जितनी कि 1938 ई म यी जब उसने यह व्यक्त किया था कि यदि अनुदार दल के अनुरूप लॉडसमा का स्गा धन किया जाता है तो "हम सविधान की सुरक्षा-मली अर्थात लाडसमा के निगमा की अस्बीकार करने की शक्ति खो बैंडिंगे। अम दल को सन्तुष्ट करने बाते विद्वाली

के आधार पर या जारा जा बठा । अभ दल का सन्तुष्ट करन बात कि काधार पर यदि लॉडसमा का पुन सगठत किया जाता है तो सम्पत्तिशानी वग में जनकी शक्ति को सकट उत्पन्न करने वाली लोकत नीय व्यवस्था की सगाज कर देने की तीत्र भावना उत्पन्न होने की आशका है। अल जो राजनीतित्र इन गर्मीर

समस्याओं के मध्य कोई रास्ता खोज सकेगा वह निस्स देह राष्ट्र की कृतनता का अधि कारी होगा। "" लेकिन लॉडसमा भी लोकत न की माँग का बहुत समय तक अवरोष

नहीं कर सकेगी। उसकी शक्ति नगण्यप्राय हो ही गयी है। संयुक्त राज्य अमेरिका का विशोध (जन्म)

संयुक्त राज्य अमेरिका का द्वितीय (उच्च) सदन—सीनैट संयुक्त राज्य अमेरिका की संधीय व्यवस्थापिका—कीग्रेस—द्विददनात्मक है। प्रथम सदन को प्रतिनिधि सदन (House of Representatives) एव द्वितीय इडर को सीनेट (Senate) की सन्ना दी जाती है। दोनो सदन समठन एव शक्तियों की हॉट्ट से अससान है।

सीनेट का सगठन सीनेट को विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली दितीय सदन माना है। अमेरिकी पार्षक में इसका स्थान त्रमुख एवं के द्वीय है। सीनेट अमेरिकी सच के घटको—राज्या—की

प्रतिनिधि सदम है। प्रत्येक राज्य को सीनेट म दो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्रार्व है। इसकी सदस्य सरवा 100 है। किसी भी राज्य को विना उसकी स्वीकृति के सीनेट में प्रारत समान प्रतिनिधित्व से वित्त नहीं किया जा सकता। 1913 ई के अमरिती सविपान के 17वें संशोधन के द्वारा सीनेटरा को राज्यों की जनता द्वारा प्रत्यक्षत निर्वा वित्त विया जान लगा है। इसके पूज सीनेट के सदस्यों को राज्यों की व्यवस्थापिकजाद्वारा निर्वाचित क्या जाता लगा है। इसके पूज सीनेट के सदस्यों को पाज्यों की व्यवस्थापिकजाद्वारा विद्यास हो जात थे। अनक अवसरों पर राज्यों की व्यवस्थापिकाएँ एक प्रतिनिधि को भी

चुनन म असमय रहती थी और सीनट म उस राज्य का कोई प्रतिनिधि नही होता था। 1901 ई म डिलवारे (Delaware) राज्य का सीनेट म काई प्रतिनिधि नहीं था।

¹⁹ Lasks op est 1952, p 138,

1890 ई से 1912 ई के काल में अनेक अवसरों पर 11 राज्यों का सीतेट में केवल एक एक प्रतिनिधि ही था। राज्य विधानमण्डला द्वारा निर्वाचन के समय हर प्रकार के अध्य साधना का सहारा लिया जाता था एवं राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के सामा य कार्यों में बड़ा व्यवधान उत्पन्न होता था। अत प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धित के पक्ष में तीज आ दोलन प्रारम्म हुआ था विसके फलस्वरूप उपरोक्त 17वा सबैधानिक संशोधन पारित हुआ था।

ए सी बीपड के अनुसार सीनेट में प्रत्येक राज्य को प्राप्त समान प्रतिनिधित्व लोकत त्रीय सिद्धा त के विपरीत है। सीनेट में मनुष्यों को नहीं अधितु मौगोलिक इका-इयों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। निवादा (Nevada) नामक कम जनतस्या बाले राज्य एव अधिक जनसप्या बाले पूर्याक जैसे वहे राज्य को समान महत्व प्राप्त है। सिकुक्त राज्य अमेरिका के 10 राज्यों में पूरे देश की आधी जनसप्या निवास करती है। लेकिन सीनेट में उनको केवल 1/5 प्रतिनिधित्व प्राप्त है। पुक्त सीनेट में उनको केवल 1/5 प्रतिनिधित्व प्राप्त है। पुक्त भीहियों, केवीफोनिया एवं देससास में 5 करोड व्यक्ति निवास करते हैं जबिक सीनेट में इन राज्यों के केवल 12 सदस्य है। अता सीनेट म असमान प्रतिनिधित्व की व्यवस्या है।

सीनेट एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कायकाल 6 वय है। एक-पिहाई सदस्य दो वय के परचात अवकाश ग्रहण कर तेते हैं। अत सम्प्रण सदन कमी एक साथ चिपटित नहीं होता। पूरे 6 वय की अवधि में प्रत्यक राज्य से सीनेट के लिए दो प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं। सीनेट की सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यतानुसार प्रत्याची के लिए यह आवस्यक है कि उसकी आयु 30 वय की होनी चाहिए, कम से कम 9 वय तक वह अमरीकी नागरिक रह चुका हो तया निर्वाचित होने वाले राज्य का निवासी हो।

सीनेट का अध्यक्ष अमेरिका का उप राष्ट्रपति होता है। सीनेट की उत्पन्ति

फाइनर का मत है कि द्वितीय सदन सम्ब भी आधुनिक राजनीतिक सिद्धात का विकास ययाभ म सवप्रयम 1787 ई के फिलाडेलफिया सम्मेलन मे अमेरिकी राजनीतिको द्वारा ही किया गया था। सीनेट के जम्म के विधेष कारण थे। सभवाद सीनेट के जम का एकमान उत्तरदायी कारण नहीं था। अमेरिकी उपनिवेशा म 1776 ई म विटिय सासन की समाप्ति के परचात स्थापित लोकत नीय सासना न असर्यमित द्वार साम की समाप्ति के परचात स्थापित लोकत नीय शासना न असर्यमित द्वार काय किया था अब अमेरिकी समाज के तहकालीन उपद्रवी एव अस्यमित लाकत तत्र ने सीनट के स्वरूप के निर्धारण म महत्वपूर्ण भूमिका निमाई थी। सम्मेतन म प्राय सभी वस्ताला ने अपने भाषणा म इसका सकेत किया है। मरीलण्ड के प्रतिनिधि मकहैनरी के कहा था कि हम भुख्य खतरा अपने सविधाना के लोकत जीय मागा स है। किसी मी सविधान म लाकत व के विपरीत प्याप्त अवरोषा की व्यवस्था नहीं है।"

^{20 &#}x27;Our chief danger arises from the democratic parts of our constitutions None of the Constitutions have provided sufficient

फिलाडेलफिया सम्मेलन के सभी सदस्य द्वितीय सदन के उद्देश के सम्बंध न समान मत रखते थे। लेकिन द्वितीय सदन का निर्वाचन कैसे हो ?, उसका कावरान एवं सदस्यों की आयु क्या हो ? उनका संगठन कैसा हो ? इन प्रश्ना के सम्बद्ध सदस्यों म विवाद था। सम्मेलन के सदस्या को इस बात का भी भय था कि वि सीनेट का कायकाल लम्बा रखा गया तो बाद मे सीनेट के सदस्य अपने कायकाल की वढा कर कही जीवन मर न कर ले और कही सीनट वशानुगत सदन म परिवर्तित न हो जाय। इसके अतिरिक्त उन्ह यह भी सम्मावना थी कि लम्बे समय तक सदस्यों न निर्वाचका स कोई सम्पक न रहने के कारण उनम राज्य क अतिरिक्त अय शास्त्र अर्थात सथ शासन के प्रति लगाव उत्पन हो सकता है। मडीसन के अनुसार 9 वर्ष का कार्यकाल पर्याप्त था। रेडोल्फ ने 7 वर्ष के कार्यकाल का सुनाव दिया था। इसके विपरीत हैमिल्टन सीनेट के सदस्यों को सदाचरण पय त कायकाल के लिए अप्रत्यक्षराहि से निर्वाचित किय जाने का पक्षपाती या। सीनेटरो के लिए 30 वप की आपु को ही है समभा गया था नयोकि कराव्या एव दायित्वा की हिंडिट से उनसे अधिक अनुभव एवं हढ चरित की अपेक्षा की गयी थी। जहां कुछ सदस्यों में दीघकाल के प्रति संदह् या, वहाँ उनमे यह भी विश्वास था कि दीव कायकाल के कारण सदन अधिक स्थायी हिंद होगा तथा वैदेशिक दायित्वा को स्थायी एव हड सदन ही मली प्रकार निमा सकता हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसे सदन के सदस्यों म उत्तरदायित्व की मावना भी अपेक्षाहरी अधिक होगी। इन परस्पर विपरीत विचारो म सम वय का परिणाम अमेरिकी सीनेट है। सविधान निर्माता सीनेट को इगलैण्ड की प्रीवी काउसिल का अमेरिकी प्रतिहर्ग मानते थे।

मीनेट की जिल्ला

H

सीनेट को विश्व के सभी द्वितीय सदनों की अपक्षा अधिक शक्तिया प्राप्त हैं। सीनेट की व्यवस्थायन या विधायी, कायपालक एव यायिक शक्तिया निम्नवत हैं

(1) विधायी शक्तियां—सीनट का विधि-निर्माण पर व्यापक नियात्रण है। गैर वित्तीय विधेयक सीनेट में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। यदि कोई विधेयक प्रतिनिधि सदन म प्रथम बार प्रस्तुत मी किया जाता है तो भी उसका सीनेट द्वारा पारित हो^{ता} आवश्यक होता है अर्थात विना सीनेट की स्वीकृति के कोई विधेयक विधि नहीं ^{वर} सकता । बित्त विधेयका का प्रथम बार प्रतिनिधि सदन म ही प्रस्तृत किया जाता है।

परन्तु सीनट को वित्त विधेयको को अपनी इच्छानुसार परिवर्तित या सद्योधित करन ना पूण अधिनार प्राप्त है। वित्त विधेयक के शीवक को छोडकर सीनेट उसक समून वलंबर को आमूलचूल रूप सं संशोधित कर सकती है। जब तक सीनट द्वारा वित विधेयका म प्रस्तावित सद्योधना का प्रतिनिधि सदन द्वारा स्वीवार नहीं विया जाता

checks against the democracy " -Me Henry of Maryland, quoted by Finer op all p 401

तव तक उसके पारित होने की कोई सम्भावना नही है । अत व्यवहारत विधेयका का स्वरूप अत्तिम रूप मे सीनेट द्वारा ही निश्चित होता है ।

- (II) कायपालक शक्तियाँ-सीनेट को व्यापक कायपालक शक्तिया प्राप्त हैं। राष्ट्रपति द्वारा की गयी नियुक्तियो को सीनेट दो-तिहाई वहूमत से अनुमीदित करती है। यह सम्मव है कि सीनेट की बिना अनुमति के राष्ट्रपति द्वारा की गयी नियुक्तियाँ सीनेट द्वारा स्वीकृत (confirm) ही न की जावे, क्योंकि नियुक्तियों के सम्बंध म 'सीनेट का सौज य' (senatorial courtesy) नामक एक प्रथा का विकास हुआ है। इसके जनुसार जिस राज्य म सघीय नियुक्ति की जाती है उस राज्य केसीनेटरोसे राष्ट्र पति द्वारा अनौपचारिक रूप सं पहले ही विचार विमश कर लिया जाता है। यदि राष्ट्र-पति इस परम्परा की उपेक्षा करता है तो सभी सीनेटर उसके द्वारा प्रस्तावित नियक्ति को विना दलीय भेदमाव के एकमत होकर अस्वीकार कर देते है। 1938 ई में राष्ट्र पति रूजवेल्ट ने 'सीनेटरा के सौज य' की सुस्यापित प्रधा की उपेक्षा की थी। उस समय सभी ने एकमत होकर उसका विरोध किया था। 21 राष्ट्रपति द्वारा की गयी सिंधगाँ भी सीनेट के दो तिहाई वहुमत से अनुमोदित होती है। यह जावश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली सभी समिया स्वीकृत हो ही जाये। 1919 ई की वार्साई सिंध को सीनेट ने अनुमोदित करने से इ कार कर दिया था। फलस्वरूप सयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रसध का सदस्य न वन सका। 1824 ई तक सीनेट ने एक भी सिंध अस्वीकृत नहीं की थी। सीनेट के समक्ष 1935 ई तक स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गयी करीब 1,100 सि घयों में से 900 सि धया उसके द्वारा स्वीकृत की गयी है और केवल 62 सिध्या को ही अस्वीकृत किया था। राष्ट्रपति को सीनेट के समक्ष किसी सि घ को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने के पश्चात उसे वापस लेने का अधि-कार नहीं है। स्मरणीय है कि सीनेट को अकेले युद्ध की घोषणा करने का अधिकार नहीं हैं। यह अधिकार काग्रेस अर्थात सीनेट एव प्रतिनिधि सदन दोनो को प्राप्त है। सीनेट राष्ट्रपति से विदेशी शनितया से वार्ता करने के लिए प्रायना कर सकती है। सामा यत राष्ट्रपति सीनेट की इस प्रकार की प्राथना को स्वीकार कर लेता है लेकिन अनि वायत स्वीकार करना आवश्यक नही है। राष्ट्रपति किसी सिध को सीनेट हारा स्वीकृत होने के पश्चात अनुमोदित करने से इ कार कर सकता है।
 - (III) यायिक शक्तिया—सीनेट को राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति एव अ'य सभी संघीय अधिकारियो पर लगाये गये महानियोगां की जाच करने का अधिकार है।

^{21 1938} इ में रूजवेल्ट द्वारा की गयी वर्जीनिया के यायाधीश की नियुक्ति की सीनट ने अस्वीवार किया था। 1943 ई म एडवड जे पलाइन (Edward J Flymu) की रूजवेल्ट ने आस्ट्रेलिया म राजदूत मनोनीत विदार था लेकिन सीनट के विरोध के कारण उसका नाम वापस ने लिया था। 1950 ई में राष्ट्रपति , हुर्मन द्वारा नियुक्त सधीय व्यापार आयोग के सदस्य की नियुक्ति को सीनट अनुमोदित करने से अस्वीकार कर दिया था।

प्रतिनिधि सदन द्वारा प्रस्ताव पारित करके महामियोग लगाया जा सक्ता है। महा मियोग को प्रस्तावित करने में सीनट का कोई अधिकार नहीं है। सीनेट द्वारा विजी अधिकारी को दोषी पाये जाने पर उसे कारावास या मृत्यु दण्ड आदि नहीं दिया जा सकता है, अधिक से अधिक उसे पद मुक्त किया जा सकता है। महानियोग प्रमाति होने के लिए सीनेट का दो-तिहाई बहुमत आवश्यक है। सीनेट म महामियोग सिद्ध होरे पर सम्बर्धित व्यक्ति को किसी भी अधिकारी द्वारा क्षमा नहीं किया जा सकता। अमी तक बारह सपीय महामियोग के मामले सीनेट के समक्ष आर्य हैं। लेकिन केवत ^{कार} मामला में महाभियोग प्रमाणित हुए है। राष्ट्रपति के विरुद्ध अय तक 1868 ई में केवल एक बार महाभियोग लगाया गया और वह मी प्रमाणित नहीं हो सका।

सीनेट मे महाभियोग की सुनवाई की एक जलग पढ़ित है। सीनेट द्वारा एक समिति नियुक्त की जाती है। समिति द्वारा महाभियोग के आरोपा को यदि सही माना जाता है तो सीनेट सम्बधित अधिकारी के विरुद्ध महामियोग की जान करती है। सीनेट जब महामियोग यायालय के रूप मे काय करती है उस समय उप राष्ट्रित उसकी अध्यक्षता नही करता अपित अमेरिकी सर्वोच्च यायालय का मुख्य वायां^{ही} अध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त सीनट को जाच के व्यापक अधिकार है। सीनेट का मुल्याकन

लिण्डसे रोगर के अनुसार "अमेरिकी सीनेट आधुनिक राजनीति का महत्वपूर्ण आविष्कार है।"²³ स्दूाग के राज्यों में "सीनेट व्यापक शक्तिया से युक्त हैं। सम्मवत जा विरव के किसी भी द्वितीय सदन का इतना वास्तविक एवं प्रत्यक्ष प्रमाव राष्ट्रीय महत्व के विषया जसे-वैदेशिक मामलो मे ही स्पष्ट नहीं है अपित् वित्त सहित समस्त सं^{दीय} विधान सम्बंधी मामूली बातों में भी स्पष्ट है। सीनेट इतनी शक्तिशाली है कि गई सयुक्त राज्य अमेरिका का एकमान प्रमावशाली सधीय सदन माना जाता है।"23 ब्राह्म ने सीनेट का मूल्याकन करते हुए लिखा है कि सविधान-निर्माताओं के मुख्य उद्देश ही सीनेट किया वित कर सकती है। वह शासन में गुरुता का के द्र है। एक तरक यह

American Senate has become the most remarkable invention of modern politics -Lindsay Rogers The American Senate (1926),

cited by Mahajan, p 177

٠,

^{22 1802} ई म सर्वोच्च 'यायालय के यायाधीश एव 1868 ई म राष्ट्रपति एण्ड, जॉनसन के विरुद्ध महाभियोग प्रमाणित न ही सका । राष्ट्रपति जॉनसन क महा भियोग की सुनवाई सीनेट म तीन माह तक हुई एव एक मत के अमाव म मही मियोग असफल हो गया ।

The powers of the Senate are very great Probably no second 24 Chamber in the world today has an influence so real and direct, not only in the most obviously national concerns, such as foreign affairs but down to the very minutest business of federal legisla tion including finance So powerful in the Senate indeed that is regarded by some as the sole affective Federal Chamber in the United States '-Strong, C F ob cit, p 213

प्रतिनिधि सदन के लोक्तन्त्रीय अनुत्तरदायित्व को और दूसरी तरफ राष्ट्रपति की राज-तानीय महत्वाकाक्षाओं को संशोधित एव नियानित करती है। सीनट की स्थिति दोनो के मध्य की होने के कारण उसकी दोना से प्रतिस्पर्द्धा एव विरोध है। प्रतिनिधि सदन विना सीनेट की सहमति के कुछ नही कर सक्ता है। सीनेट अपने विरोध द्वारा राष्ट्र-पति को रोक सकती है । यह सीनेट की नकारात्मक सफलताएँ हैं । सकारात्मक हृष्टि से भी सीनेट अपने को लोकप्रिय एव महान बनाने में सफल हुई है ।"25 जॉज वाशिंगटन ने एक बार कहा था कि सीनेट तो एक तस्तरी है जिसमे प्रतिनिधि सदन की उबलती चाय को शीतल किया जाता है।²⁸

"कुछ ऐसे काम है जिन्हे राप्टपति और सीनेट बिना प्रतिनिधि सदन की सह मित के कर सकते है, कुछ को प्रतिनिधि सदन एवं सीनेट विना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कर सकते है, लेकिन राष्ट्रपति एव प्रतिनिधि सदन विना सीनेट की स्वीकृति के बहुत कम काम कर सकते हैं।"

सीनेट की शक्ति एव प्रभाव के कारण निम्न है

- (1) विधायी क्षेत्र मे ही केवल सीनेट एव प्रतिनिधि सदन की शक्तिया अस-मान नहीं हैं अपित सीनेट को महत्वपूर्ण कायपालक एव यायिक शक्तिया भी प्राप्त हैं। वित्त विधेयका को पूणत सद्योधित करने का उसे अधिकार प्राप्त है। अत सीनेट काग्रेस की एक अधीनस्य बाखा मात्र नहीं है अपित वह अपनी बक्ति के कारण एक तरफ राष्ट्रपति पर और इसरी तरफ प्रतिनिधि सदन पर नियात्रण रखती है।
- (2) सीमेट का आकार छोटा है जिसके फलस्वरूप इसके द्वारा प्रभावपूण दग से विचार विमश सम्मव है। सीनेट के सदस्यों में एकता की भावना पायी जाती है। वास्तव में सीनेट एक अब म पारस्परिक सुरक्षा का समुदाय (a mutual protection society) है। उसकी एकता में ही उसकी स्वत त्रता एवं प्रमाव डालने की क्षमता निहित है। सीनेट जीजो और जीने दो' तथा 'किसी को भी अपने विशेषाधिकारा का अतिनमण मत करने दो' के सिद्धा तो को मा यता देती है।
 - (3) सीनेट के सदस्यों का कायकाल अपेक्षाकृत लम्बा है । इसके अतिरिक्त

Jan op cit p 176
26 The Senate was once described by George Washington as 'the saucer in which the boiling tea of the House was cooled '-Cited by Mahajan, p 176

²⁵ Senate has succeeded by effecting the chief object of the father of the Constitution, viz the creation of a centre of gravity in the government, an authority to correct and check on one hand the democratic recklessness of the House, on the other the monarchial ambition of the President Placed between the two, the Senate is necessarily the vital and often the opponent of both the House can accomplish nothing without its concurrence The president can be checkmated by its resistance These are so to speak the negative successes, on its positive side it has succeeded in making itself eminentand respected "-Lord Bryce, cited by Maha-

सीनेटरों को अधिकाशत पुन निर्वाचित किया जाता है, अत वे अपने कायक्षत्र में दूव दक्ष होते हैं और उन्हें सार्वजनिक मामला का व्यापक ज्ञान तथा अनुमव होता है। वे दल के प्रमावक्षाली नेता भी होते हैं।

(4) सीनेट में सदस्यों को वाद-विवाद की पूण स्वत तता होती है। इस और कार का कमी-कमी दुरुपयोग भी किया जाता है लेकिन इससे अल्पसस्यक सदस्ये में अपने विचार एवं ट्रिटकोण को उपस्थित करने का अवसर प्राप्त हो जाता है।

(5) सीनेट की जाच करने की शिवत प्रधानक है। वह हर प्रकार क मामलों में विशेष रूप से-जाँच कर सकती है। सिद्धा तत सीनेट को जाच करने का अधिनार इसलिए प्राप्त है तािक जाच के माध्यम से वह विधि-निर्माण के लिए आवश्यक तथ्य एवं सामग्री एकिंचित कर रखें। सीनेट द्वारा विशेष समस्याओं के अध्यम के विष् मी सिमितया नियुक्त की जाती है। इस प्रकार सीनेट अपने को विमिन्त सीनित्या में विमाणित कर लेती है और उहीं के माध्यम से काय करती है। इस सिनित्या में वाचावश्यक कागजात प्राप्त करने एवं शायप्युवक साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार है। वह किसी भी व्यक्ति को अपने समक्ष साक्ष्य देने के लिए बाध्य कर सकती है। इत सीनित्यों की विशेष मामलों से सम्बिधित सीनित्यों में किए बाध्य कर सकती है। इत सीनित्यों के समक्ष अधिकार हो। सीनित्यों के सामक्ष अधिकार शिवत सीनित्यों से साक्ष्य देने में घवराते है। सीनित्यों के सामक्ष अधिकारा अधिकारी उपस्थित होने एवं साक्ष्य देने में घवराते है। सीनित्यों की कायवाही गुप्त नहीं होती। सीनित्यों के द्वारा सीमितियों में साक्ष्य देने बाला है ऐसे प्रका पूर्व लोते हैं एवं सूचनाएँ प्राप्त करने का प्रयत्त किया जाता है जितक हि साक्ष्य देने वालों की विश्व नित्यों हो। सिन्त हो। सिन्त है। वह अधी की कायवाही गुप्त नहीं होती। सीनित्यों के ताल के विश्व मामन है। वह साक्ष्य देन वालों के विश्व नित्यों हो। सकती है एवं उसकी चरित्य हाया भी समन्त है। वह स्थानक एवं हु खब स्थिति है। अत आँग और रे का कथन है कि "सीनेट की प्रावित्य प्रतिव्या में समन्त है। वह सिन्त हो। विश्व प्रतिव्या में सम्पन है। वह साक्ष्य होने वालि हो। विश्व प्रतिव्या में सम्पन है। वह स्थान सिव्या में सम्पन है। वह स्थान स्थान हो। वह सिव्या में सम्पन है। वह स्थान सिव्या में सम्पन है। वह साक्ष्य सिव्या में सम्पन है। वह स्थान हो। वह सिव्या में स्थान सिव्या में साक्ष्य होने साक्ष्य हो। वह सिव्या में साक्ष्य होन सिव्या में साक्ष्य हो। सिव्या में साक्ष्य होने सिव्या में साक्ष्य होने सिव्या में साक्ष्य होने सिव्या में साक्ष्य हो। सिव्या में साक्ष्य होने सिव्या में सिव्या सिव्या

पहले की अपेक्षा सीनेट कम अनुवार है। उसमे पहले की मीति सम्पत्तिशाली वग का बाहुल्य एव प्रावत्य नहीं है। यह प्रतिनिधि सदन की अपेक्षां अधिक उदार एव प्रगतिशील भी है। इसके बाद दिवाद का स्तर निस्स देह जैवा है। कमी कमी सीनेट के सदस्यों में प्रतिनिधि सदन के सदस्यों की माति पक्षपात एव मावना भी प्रधानता विखायी देती है। लेकिन सीनेट के अधिकाश सदस्य अपने विचारों को स्वतंत्र

रूप में ही व्यक्त करत हैं।

सीनेट की बक्ति एव प्रमाव से सम्बाधित तथा उसकी कायपद्धति क परिणामा

का फाइनर न उल्लेख किया है। ²⁷ वे निम्न हैं

(1) सीनेट प्रतिनिधि सदन से अधिक शक्तिशाली है। उस प्रतिनिधि सरन के समान ही विधि निर्माण के अधिकार हैं। विस्त विधेयका क सम्ब ध म उस व्यापन अधिकार है। वह जनम पूछ सधाधन कर सकती है। उसे नियुक्तिया एव सचिया को अनुमेन्न करन की धार्फि है। इन व्यापक धक्तिया ने कारण सीनट के सदस्य अपन राज्य पढ़े स्त में प्रतिनिधि सदन के सदस्या नो प्रमावित करने म सफल होते हैं। नियुक्तिया

²⁷ Finer, H op cit pp 420 22

सम्बाधी सीनेट की शक्ति के द्रीय होती है और नीति-निर्वारण में मोहरे का काय करती है।

- (2) सीनेट म प्रत्येव सदस्य को विचार व्यक्त करने की अनिया नित स्वत निता है। विसी भी सीनेटर को विधि निर्माण एव प्रशासन के काय म वाधा उत्पन्न करने से रोकने के लिए सबसम्मत निषय की आवश्यकता होती है। किसी अनावश्यक विषय पर निरत्तर भाषण देकर सीनेट के काय को जनके सदस्य ठप्प कर सकते है। इस अस्त का प्रयोग अधिकारात अल्पसस्यक सदस्यो द्वारा उस समय किया जाता है जबकि सीनेट के बहुसस्यक सदस्य शी घ्रतापूबक किसी महत्वपूण विधेयक को पारित करना बाहते हैं या कमी-कमी किसी विधेयक को समाप्त करने के इच्छुक होते है। एक व्यक्ति निरतर बोलत रहकर सीनेट के बाय को जबस्द कर सकता है। इस प्रथा को फिली-वसटरिंग (Filibustering) कहते हैं । इसके कारण सदन का पर्याप्त समय व्यय ही नप्ट हो जाता है। 8 इस दूपित प्रथा को रोक्ने के लिए 1917 ई म एक अधिनियम वनाया गया था जिसके द्वारा यह व्यवस्था की गयी थी कि यदि 16 सदस्या द्वारा विचाराधीन विधेयक पर विवाद को समाप्त करन का प्रस्ताव किया जाता है और दो तिहाई बहुमत से सदस्यगण उसका समयन करते है तो विवाद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। 29 इस अधिनियम के कारण फिलीबसटरिंग कम तो हुई है लेकिन समाप्त नहीं हुई है। स्मरणीय है कि फिलीवसटर का प्रयोग कभी कभी केवल घोडे ही सदस्य करते हैं।
 - (3) सीनेट म समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है अर्थात सभी वडे एवं छोट राज्या को दो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। इसके कारण देश के विभिन्न आधिक एवं सामाजिक समुद्रा को असमान प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है।
 - (4) दोनो सदनो में उत्पन गतिरोध को दूर करन के लिए उपगुक्त विधान का अमाव है। दोनो ही सदनो के कछ सदस्या को नियनत क्या जाता है जो कि पार
 - 28 1903 ई म सीनेटर टिलमन ने किन बायरन के 'बाइल्ड हैरल्ड नामक काक्य का उस समय तक पाठ करने की घोषणा की थी जब तक विवादास्पद अहा को विषेपक म से निकाल नही दिया जाता। एक दूसरे जनसर पर सीनेटर रात मर योवते रहे। सीनेटर चायड ने बनातार 6 घष्टे 50 मिनट तक भाषण दिया था। 1908 ई म सीनेटर कालेट ने 30 घष्टे एव 1953 ई म मास आफ आगन न 22 घष्टे 26 मिनट तक भाषण दिया था।
 - १ 22 पण्ट 26 मिनट तक मापण दिया था।
 29 इस नियम का उपयाग सक्त्रयम 1919 ई म वासाई मि घ पर वाद विवाद को समाप्त करने के लिए किया गया। उसके वाद तीन वार इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। 1949 ई मे इस नियम को पुन सलाधित किया गया जिसके अतगत कुल सदस्या के 2/3 बहुमत को वाद विवाद के अत के लिए अनिवाय किया गया। 1917 ई के नियमानुसार उपस्थित सदस्यों के ही 21 वहुमत को आवस्यकता होती थी। 1959 ई म 1949 ई को व्यवस्था को सशोधित करने 1917 ई की व्यवस्था को हो देशीकार किया गया।

स्परिक वार्ता द्वारा विवाद का हस बूबते है एव उसे स्वीकृति क लिए दोनो सता से समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। प्राय यह सदस्य गुप्त सौदवाजो क द्वारा विश्व सक्षम हल पर पहुँचत है। लेकिन इस समिति द्वारा सदम म सूचना प्राय सत्र क अन्त म ही रही जाती है। सदन के पास उस समय पुन निचार के लिए पर्याप्त समय नही रहा। विश्व व्यवस्या प्रतिनिधि एव उत्तरदायी धासन की पारणा की हर्ष्टि से अनुचित है। 1946ई को अस्त विधि (Law of August, 1946) के द्वारा सदन एव समितिया की नम प्रणाली मे कुछ परिवतन किये गये है। वजट सम्ब धी मितरोध पर विचार करने के लिए एक सबुक्त समिति की व्यवस्था की गयी है।

लासको ने सीनेट पर मत व्यक्त करते हुए कहा है कि "बहुत कम व्यक्त पिकाओ म इतना अधिक समय नष्ट होता है और उससे भी कम व्यवस्मापिकाओं में लागरोलिंग (Logrolling) को एक पूण कता के रूप म विकसित दिया गया है। लागपालिका के प्रति सीनेट का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। यह एक ऐसी सस्याहै ये नियुक्तिया के प्रवन पर ही केवल एकमत होती है। फिर भी यह अमरिकी राजनीतिक प्रणाली की महान सफलता है। यह इसकी अभूतपुत्र समता है कि सामाय नामिक में अपने सम्बच्ध म रुचि उत्पन्त कर सकी है और बहुत कम व्यक्ति इसकी वस्त्या के लोग का सवरण कर पाते है। यह राष्ट्रपति की निर्कुशता एव महत्वाकामा "प महत्वपूण अवरोध के रूप से काय करती है। इसके सदस्य कमी कमी सकीणमनीभा के होते है पर सु वे प्रतिनिधि सदन की सकीणता से सवधा मुक्त होत हैं।"

क्या सीनेट की स्थापना के उद्देश्य पूज हुए हैं ?

सीनेट की स्थापना के प्रमुख उद्देश राज्या के अधिकारा की सुरक्षा एव राष्ट्र पित की निरकुसता को कम करना था। यह दो समस्याएँ अमेरिकी सविधान निर्मावकों के समक्ष थी और उपद्रवी एव अनियत्त्रित लोकत न का सीमित एव नियत्त्रित करने का समक्ष थी और उपद्रवी एव अनियत्त्रित लोकत न का सीमित एव नियत्रित करने का प्रमान पा । कलस्वरूप राज्या के अधिकारा की रक्षाय प्रत्येक राज्य को सीनेट म समत्त्र प्रतिनिधित्व दिया गया। राष्ट्रपति पर नियत्त्रण के निष्ठ नियुक्तियों एव वर्दीक्षक मामला मं सीनेट की दो तिहाई बहुमत से सहमति आवश्यक बना दी गयी। परप्रपुरवर्ती घटनाओं की सभीक्षाओं से यह स्पष्ट है कि राज्या के अधिकारा की सुरक्षा नहीं है है। इसका एक मूल कारण यह है कि सीनेट म दलीय अगुवासन प्रतिनिधि सदन नी अपेक्षा होता है। एक राज्य के एक ही दल के दो प्रतिनिधि अपनी अपनी इच्छानुसार प्रवक्त गुक्क पृत्यक मत्र तह हैं। 1913 ई के बाद तो धीनेटरा पर दलीय निय त्रण और भी दीजा हो गया है क्योंकि वे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति हो निर्वाचित होन तमे हैं। बत होता हो गया है क्योंकि वे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति हो निर्वाचित होन तमे हैं। वर्द सोता निरद पृत्यक प्रवक्ष देता के हैं वर्द होता सीनेटर एक साथ काय करते। वर्द यात्रा सीति र पृत्यक्ष प्रतिनिधित्य नी भी सी स्वाच साम करते। वर्द प्रवाच काय करते। वर्द सामाजिक परिस्थितियों ने अमेरिनी सधीय सरकार की शिन्द्रया म वर्षाव्य वृद्धि कर सी हो। साम असित्या म वर्षाव्य वृद्धि कर सित्या स्वाच करते। वर्ष सामाजिक परिस्थितियों ने अमेरिनी सधीय सरकार की शिन्द्रया म वर्षाव्य वृद्धि कर सी हो।

राष्ट्रपति पर जहाँ तक निय त्रण का प्रश्न है, लास्त्री के अनुसार राष्ट्रपति

की नीतिया के सम्बाध में प्रभावकारी नियं प्रणकरते का सीनेट एक सवयानिक उपकरण है। पर्याप्त शक्तिशाली एव प्रभावशाली राष्ट्रपतियों को भी उसके समक्षा भूकता पड़ा है। रूजवेल्ट तथा विरुत्तन भी सीनेट की उपसा नहीं कर सके थे। सीनेट के विरोध के कारण राष्ट्रपति कूलिज उस व्यक्ति को एटोर्नी जनरल न बना सके जिसे वे बनाना चाहते थे और राष्ट्रपति निक्सन को वाटरगेट काण्ड के कारण पद से हटना पड़ा।

अत सीनेट राष्ट्रपतियो पर नियात्रण करने म सफल रही है।

अमेरिकी सीनेट तथा बिटिश लॉडसभा दौना ही द्वितीय सदन है। दौना म पर्याप्त असमानताएँ है। सगठन की दृष्टि से लॉर्डसमा अधिकाशत वशानगत मनोनीत एव वृहद सदन (1,010 सदस्य) ह तो सीनेट निर्वाचित एव 100 सदस्यो का लघु सदन है। सीनेट के सदस्या का कायकाल 6 वप है जब कि लाडसभा की सदस्यता जीवन पयात होती है। शक्ति की इष्टि से लॉडसमा की तुलना में सीनेट अधिक शक्तिशाली है। विधि निर्माण के क्षेत्र में लॉडसमा को गैर वित्तीय विधेयकों के सादम म केवल 1 वप की निलम्बकारी शक्ति प्राप्त है। वित्त-विधेयको के सम्बाध मे उसकी घक्ति नगण्य है लेकिन सीनेट को विधि निर्माण म प्रतिनिधि सदन के समान ही शक्तिया प्राप्त है। केवल धन विधेयक का प्रारम्म प्रतिनिधि सदन मे होता है लेकिन सीनट उसम आमुलचल संशोधन कर सकती है। सीनेट को नियुक्तियो एव सिधियो को अनुमोदित करने की शक्ति है जो लाडसमा को प्राप्त नही है। लॉडसमा सर्वोच्च अपीलीय पायालय है एव लॉडों के देशद्रोह एव अय गम्भीर आरोपा की जाच करता है। सीनेट केवल उच्च पदाधिकारिया के महाभियोग के मामलो को सुनती है। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन में कॉम स सभा लॉडसमा की शक्तिया एवं संगठन में परिवर्तन कर सकती है लेकिन प्रत्येक राज्य को सीनट म प्राप्त समान प्रतिनिधित्व सं उस विचित नहीं किया जा सकता। ब्रिटेन में लाउसभा तथा काम स समा म समय की स्यिति म लॉडसमा की पराजय निश्चित है लेकिन अमेरिकी सीनेट एव प्रतिनिधि सदन म विरोध की स्थिति म अधिकाशत सीनेट की ही विजय होती है।

फ्रान्स का दितीय सदन—सीनेट

फा'स के ततीय (1875 ई) के बतुय (1946 ई) एव पचम (1958 ई) गणराज्या के सविधानों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गयी है। उच्च सदन को ततीय एव पचम गणराज्यों के अत्तगत सीनंट एव चतुय गणराज्य के अन्त-गत 'गणराज्य परिषद' (Council of the Republic) को सना प्रदान की गयी। 141

³⁰ तुतीय फेच गणराज्य की स्थापना 1870 ई म हुई थी वेकिन उसक सवियान के निमाण म 5 वप लगे थे। सवियान तीन विधिया —फरवरी 25, फरवरी 24 एव जुलाई 16, 1875 ई म समझीत है।

³¹ त्तीय गणराज्य के अन्तगत निम्न सदन को डेपुटीब सदन (Chamber of Deputies) तथा बतुख एव पदम पणराज्या म नदानल असम्बन्ती (National Assembly) क नाम से पुकारा गया ।

284 | अधुनिक शासनत त्र

सीनेट की उत्पत्ति एव विकास

फास य द्वितीय सदन के निर्माण तथा विकास का भी अपना इतिहास है ! कास के राजनातिकारिया को लोनप्रिय सप्रमुता म विस्वात या। वे डीतीवर्ग (Delolme) एव मोन्देस्वयु (Montesquieu) की ब्रिसदनीय व्यवस्थापिका के विचार को स्वीकार न कर सने। रूसा से अव्यधिक प्रमावित हान के कारण एस्डर

- नीम व्यवस्थापिका की ही स्थापना की गयी थी। यह दो कारणा सं आवस्यक मी वा
- (1) मातिकारी यह प्रमाणित करना चाहत वे कि सप्रमुवा जनता म निहित है, हण (2) सभी व्यक्ति समान है। फलत 1791 ई एवं 1793 ई के सनिवास में दिख नीय ब्यवस्था को नहीं अपनाया गया था। बितीय साम्राज्यकाल (1852 70 ई) के अत्तमत राष्ट्रीय ममा (National Assembly) ही एकमात्र सदन वा और उनमे अकेले ही नेपोलियन ततीय का सामना किया था।

तृतीय गणराज्य के 630 सविधान निर्माताओं म से 400 सदस्य राजत व न विद्यास करते थे तथा वे सभी राजत न की पुनस्थापना क लिए हट-सकरण थे एव उसक अभाव में ऐसी सस्याओं की स्थापना कर देना बाहते थे जिनके द्वारा उपपुक्त अवसर पर राजतन्त्र की स्थापना हो सके। दिलीय सदन का वशानुगत आधार गर सगउन अलोकता निक होने और मनानयन की रीति म राजत शीय भावना की गर आने के कारण उच्च सदन के निर्माण के लिए नियंचन की रीति अपनान का निश्च किया गया था। यह निरुचय अल्पसस्यक वासपची एवं विशिषपची स्तो के मध्य नमभीते का परिवास था। वृतोय गणराज्य की सीनेट

यह अप्रत्यक्ष रीति स गठिन सदन था। सीनेट के सदस्यां को निर्वाचित कर्रः वाले तिर्वाचक मण्डल म डिपाटमण्ड (Department) के डिप्टीज, डिपाटमण्ड क वर रेत काउत्तिल के सदस्य, उपन्काउतिको (Ariondisement) के सन्त्य तथा नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि होते थे। भीनेट के सदस्या का कायकास 9 वय या और एक तिहाई सदस्य प्रति तीन वय बाद चुने जाते थे। 40 वय से कम आयु का कोई भी फंच नागरिक सीमेंट का सबस्य नहीं ही सकता था। 1884 ई तक सीमेंट में 300 सदस्य थं जिनमे स 225 सदस्य विपाटमेण्टो द्वारा एवं 75 राष्ट्रीय समा द्वारा चृते जात थे। तगठन की इस विधि से छोटे कस्यूना को सीनट में अधिक प्रतिनिधित्व प्रार्प हों जाता या। वामपक्षी गणत नवादी सीनट की आजीवन सदस्यता का अन करना चाहते वे और छोटे कम्यूनों को जो अतिरिक्त प्रतिनिधित्व प्राप्त वा उसे क्य करता चाहते हो । 1883 ई के निवाचना म गणत जवादिया का अपकाशृत अधिक बहुमत प्राप्त हो गया और 1884 ई म सामाय विधि द्वारा सीनट के निमाण की रीति म मशोधन किया गया और प्रत्येक जाजीवन सदस्य मो मत्मु के उपरात्त निर्वा चित मदस्य की नियुक्ति का विधान किया गया।



से प्रका पूछने एव सूचना प्राप्त करने तथा जांच की व्यवस्था द्वारा सीनेट प्रगाल पर निय त्रण रसती थी। उसके द्वारा अविक्वास एवं निया के प्रस्ताव भी पाति कि जाते थे । सीनेट अपने जायोगां (Commissions) के द्वारा भी मनिया पर निवस रखती थी।

तितीय गणराज्य की सीनेट को एक आदश्च दिवीय सदन माना जाता था। स न तो नहुत अधिक सिक्तसाली था और न बहुत कमजोर ही था। पुनरों के बनुतार ्रा पष्टुण जावण जाताजाला वा जार न बहुत क्ष्मजार हा वा। उत्तर क्रु जनमत के मावावेश के सामने धीरे धीरे फुकना चाहिए जेकिन जब यह निश्चित हो जाय कि हवा का रेख एक निश्चित दिशा में हैं तो उसे तुल कुल जाना चाहिए। व्यवहार म सीनेट ने इसी प्रकार आचरण किया है। अत सीनेट एक आदश डितीय संदत्त है।" फाइनर के अनुसार "सीनेट ने अपने निर्माताओं से भाकाक्षाको एव भाकाक्षा को अधिकारक अनुसार 'सामद न अपन (१९१०) । प्राह्म के अनुसार 'सामद न अपन (१९१०) । प्राह्म के अधिकारक प्राप्त किया था। वह संस्था पर निस्त्य है प्रतिक में था। सीनेट यह दो कारणों से कर सकी भी—(1) वैस्वस की असिकियिया। एव (2) इसक फलस्वरूप देश नेपा दोनों सदनों म संयक्त दलीय संगठन का बिहाहा मिनेट अपने को संघोधन एव अवरोध के के द्व के रूप म ही बनाये रख सकी। इसी म उसने त तीप रखा। कभी कभी महत्वहीन मामला के यारे में ही उसने विधिक्ष के निर्माण म पहल की थी। 32 चतुर्वं फ्रेंच गणराज्य का हितीय सदन—गणराज्य परिपद

चतुष गणराज्य के संविधान में भी हिसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना व गयो थी। इतने द्वितीय सदत को गणराज्य परिषद (Council of the Republic) की सक्षा ही गयो । ततीय गणराज्य की सीनेट की मीति यह भी अप्रतक्ष सीति है। निर्वाचित संदन या। संताम भणराज्य का संनिद्ध की मीति यह मा अन्नत्वस पाप प्रमाणक परमवत इंतना कारण फान्स की जमन मारूप में दिवाम सदन का उल्लंख नहां गान्स की जमन आधिपत्य है मुक्ति (1944 ई) के पहचात अत्याप इतका कारण काल्य का जमन आध्यस्य से मुक्ति (1944 है) के परना अनिक मान्या ने अत्यापन के मुक्ति (1944 है) के परना अतिम प्राह्म में अत्यात ही कमजोर दितीय सदम का सुमान दिया था । सावपार के आकार कमीर करा है कमजोर दितीय सदम का सुमान दिया गया था शेर सदस के आकार अविध आदि की वारे में विधि हारा व्यवस्था का उल्लेख था।

1948 है के अधिनियम के अनुसार सीनेट की सदस्य-सस्या 320 निश्चित की गयी । इन 320 सरस्या म से 200 हिमार्टमेण्टा तथा 50 निम्म सरस्य-सार्थेय तमा (National Assembly) है। त निर्वाचित किय जाते थे। सेंप 20 स्थान समु पार के मेंब उपनिवेशी एव अवासी का सीवियों को अतिनिधित्व हेतु अदान किये गरे है। सीनेट का कायकाल 6 वर्ष निहित्तत किया गया था। प्रतितीन वप बाद आये हस्य वेबकास महण करते थे। मणराज्य परिषद की सहस्यता के सिए मुनतम बागु 35 क्व नियत की गयी थी। स्थित की संदर्भता का स्वर् यूनवा भारत की स्थान की स्थान की संदर्भता की स्थान की संदर्भ की 32 Finer, H op cit, p 431

को सदस्यता से बचित कर दिया गया था। परिषद की शक्तिया अत्य त सीमित थी। 33 विधि निमाण के क्षेत्र मे उसका बहुत कम नियागण था। उस एक परामशदायी सदन की सजा दे सकते है। यदि कोई गैर वित्तीय विधेयक प्रथम बार परिषद मे प्रस्तुत कर मी दिया जाता था तो उस पर विचार नहीं हो सकता था क्योंकि ऐसे विधेयको पर सवप्रथम परिष्टिय कारी विधेयक को अधिक से अधिक केवल 2 माह तक ही रोक स्वक्ती थी। वित्त विधेयकों के सम्ब ध मे तथा आपति कार म अस अवधि को भी घटाया जा सकता था।

गणराज्य के राष्ट्रपति के निर्वाचन में सीनेट को अधिकार प्राप्त था। यह सवैषानिक समिति के तीन सदस्यों को भी चुनती थी। मिनमण्डल परिपद के प्रति उत्तरदायी नहीं था।

चतुय गणराज्य की परिषद विश्व के सबसे कमजोर द्वितीय सवना मे थी। अत आलोचका का कथन है कि का स में इस सदन के रूप में खायात्मक द्विसदनवाद (Shadowy Bicameralism) या अपूज द्विसदनवाद (Incomplete Bicameralism) या मुद्द एकसदनवाद (Tempered Monocameralism) की स्थापना हुई थी। यह सदन काय समिति (Council for Action) न होकर विश्वार-विमञ्च की परिषद (Council for Reflection) थी। यह किसी तरह मी पुरानी सीनेट की स तान नहीं कहीं जा सकती। वेकिन काटर, रेचने एव हेज का मत है कि परिषद को विधि-निमाण भी अस्य त सीमित व्यक्ति प्राप्त होने पर भी उपने राष्ट्रीय समा द्वारा शीघता एव मावावेश में पारित विधेयको म संशोधन प्रस्तावित किये एव इन संशोधनों को राष्ट्रीय समा खारा शीघता एव मावावेश में पारित विधेयको म संशोधन प्रस्तावित किये एव इन संशोधनों को राष्ट्रीय समा अस्वीकार नहीं कर संकी थी। परिषद की कायपदित से यह स्थप्ट हुआ है कि सीमित शक्तियों से मुक्त वित्तीय सदन मी पर्याप्त नैतिक शक्ति शत सकता है। 11 परिषद की कायपदित से अनुसार, गणराज्य परिपद की स्थापना से ततीय गणराज्य की सीनेट की घटना का वदला वित्या गया। 18

पचम फ्रोंच गणराज्य (1958) का द्वितीय सदन-सीनेट

पचम फ्रेंच मणराज्य के द्वितीय सदन सीनेट के सगठन में कोई मौलिक अंतर नहीं है। सीनेट अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित सदन है और फास के उपनिवेशा म नियास करने वाले फ्रेंचजनों को सीनेट में प्रतिनिवित्व दिया गया है। सदस्या का नाय काल 9 वप है। एक तिहाई सदस्य प्रति तीन वप के पश्चात अवकाश ग्रहण

^{33 1954} ई के सर्वेषानिक संशोधन द्वारा परिषद की शक्तियां में कुछ परिवतन किये गये थे जो नगण्य थे।

³⁴ The Council of the Republic in atleast giving a demonstration of the fact that even a Second Chamber with very limited powers can exert considerable moral authority —Carter, Ramney and Herz op cit, p 139.

³⁵ Thus the audactty of the Senate of the Third Republic has avenged '-Finer, H op att, p 433

करते हैं। चतुष गणराज्य के दिवीय सदन की सरया से इसकी सदस्य-सस्या का है। कुल सदस्य-संस्था 307 में से 225 सदस्य का स के डिपाटमेण्टों 6 सदस्य हवी फेब निवासिया एव होष फेब उपनिवेशो का प्रियिनिधित्व करते हैं। अल्बीयस साम उपनिवेश को 32 स्थान प्राप्त थे, तेकिन उसके स्वतन्त्र होने के पश्चात यह हाल कम हो गयी है।

पचम गणराज्य के व्यवगत दोनो सदना के सम्बंध ततीय गणराज ह समान ही है। सीनेट राष्ट्रपति हारा प्रस्तावित विधेयक के माम में वामा उत्पन्न का औ सकती है। दोना सदनो के मध्य उत्पात विवाद के समाधान के लिए सविधान म नीर व्यवस्या नहीं है। जिस विषेयक पर दोनो सदन एकमत नहीं होते, वह दोना केम निरंतर विवाद का कारण बना रहता है। ऐसी स्थिति म विशेष परिस्थित म शहर को हत्ताक्षेप करने का अधिकार है। यदि दोनो सदना म विधेयक पर वो बार विवार ही वुका हो तो सरकार को एक आयोग की स्थापना की मांग करने का अधिकार है जिसमें कि प्रत्येक सदम के तीन सीन सदस्य होते हैं। आयोग यदि किसी निश्चित परिवास पर पहुँचता है तो उसके अनुसार उस विधेयक को दोनो सदनो द्वारा पुन पारित क्या जाता है पर तु यदि आयोग के प्रयत्ना का कोई परिवास नहीं होता या विधयक किसी एक सदन द्वारा पुन अस्वीकार किया जाता है, तो दोना सदनो को पुन किसी निवर पर पहुँचन के लिए प्रयत्न करने का अधिकार है। वामाय विधियों के समय व सीनट के विरोध को निष्प्रमानी करने के लिए यह वाबस्यक है कि निम सत (राष्ट्रीय समा) जह अपने सामा य बहुमत सं पुन पारित करें। यह व्यवस्था वित विभेषका एव मूल विधिया (Organic Bills) पर लागू नहीं होती। वित विधया को राष्ट्रीय समा म ही सवमयम मस्तुत किया जाता है। राष्ट्रीय समा की तुलना म सीनेट की स्थिति एक अधीनस्य सदन की है।

वैक्ति अनेक अस सर्वेमानिक उपवास उमकी स्थितिको हेंद्र करने म याग देते हैं, जवे---

(1) चीनट वा अध्यक्ष गणराज्य के राष्ट्रपति के अस्त्रस्य होने की अस्त्रस्य म उत्तका स्पान ग्रहण परता है और नवीन राष्ट्रधात के अस्वस्थ हान का स्वाप्त का अस्वस्थ हान का स्वाप्त का रहता है।

(2) राष्ट्रीय समा ने विपटन की घोषणा नरने से वूच राष्ट्रपति के तिए वीनद के बच्चस स परामन करना आवस्यक है।

(3) सीनट के अध्यक्ष को विश्वेष परिस्थितिया म रिसी विषेषक को सर पानिक समिति म विचार हेतु भेजन का अधिकार है। वह इस समिति के तीन संस्था मा भी मनोनीत परता है।

(4) सोनट व नाम राष्ट्रपति का सन्धा नेजन का अधिकार है। इसके जीत भेनमत समृह के जिल पारित राष्ट्रीय सेना का आपनार है। ६१४ रू र अका 5 आवस्य ह हाना है।

¥ 7 77 Tr. 177

(5) मपानमात्री हा यह अधिकार है हि वह जब पाद तब सीनट से सामा उ

नीति की स्वीकृति की माग कर सकता है लेकिन मित्रमण्डल राष्ट्रीय समा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। राष्ट्रीय समा मे मित्रमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर या कोई अय विवेचक या सामाय नीति या कायक्रम सम्ब थी प्रस्ताव अस्वीकृत होने पर मित्रमण्डल को त्यागपत देना पडता है। सीनेट को मित्रमण्डल के प्रति अविश्वास व्यक्त करने का अविकार नहीं है।

- (6) सीनेट को उच्च 'यायालय (High Court of Justice) मे राष्ट्रीय समा के समान ही प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है।
- (7) सिवधान के अनुसार फेच ससद अर्थात सीनेट सहित राष्ट्रीय समा को युद्ध की घोषणा करने का अधिकार है।

पत्रम गणराज्य की सीनेट अपने पूजवर्ती काजिसल ऑफ दी रिपिन्सिक की तुलता में अधिक शक्तिशाली है। स्मरणीय है कि इगलैंग्ड की लाडसमा एव फ्रान्स की सीनेट (ततीय एव पत्रम गणराज्य) एव गणराज्य परिपद (चतुव गणराज्य) एकात्मक राज्या के द्वितीय सदन है लेकिन इनके समठन एव शक्तियों में पर्याप्त अत्य है। लाडसमा प्रधानत वशानुगत एव मनोनीत है तो फ्रेंच सीनेट निर्वाचित सदन है। लेकिन दौना सदमों की शक्तिया जपने अपने जिम्म सदमा की शुलता में कम है। सीनेट (पदम गणराज्य) की युलना में लॉडसमा की शक्तिया भी कम है। पीनेट

कनाडा का द्वितीय सदन—सीनेट

कताडा के वनमान सविधान की स्वापना ब्रिटिश नाय अमरिका एक्ट के द्वारा हुई है। यह सविधान 1 जुलाई, 1867 ई से कियाबित हुआ है। कनाडा का सविधान सपीय है।

कनाडा की व्यवस्थापिका द्विसदनारमक है। प्रथम सदन को कॉम स समा (House of Commons) एव द्वितीय सदन को सीनेट (Senate) की सज्ञा दी गयी है। सीनेट का सगठन

सीनेट के सदस्यों को जाउन द्वारा गवनर जनरस—व्यवहार में मित्र-परिपद (प्रधान मात्री)—के पराश्वा पर मनोनीत किया जाता है। प्रत्यकसीनेटर की आयुक्तम से कम 30 वद होनी चाहिए एवं उसे जामजात या ब्रिटिश प्रजाजन होना चाहिए तथा

³⁶ स्टाग न एकतन्त्रीय राज्य में निर्वाचित द्वितीय सदन का दूसरा उदाहरण इटली के नवीन गणराज्य की सीनेट का दिवा है। पहले इटली की सीनेट मनानीत थी लेकिन नवीन सविधान के अत्यक्त यह केनीय आधार पर निर्वाचित सदन है। 5 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा समाज विनान एक कला आदि के क्षेत्रों में स्थाति वे आधार पर मनोनीत किये आते हैं। इसके अविरिक्त गणराज्य के भूतपूत राष्ट्र पति भी सीनेट के सदस्य होते हैं। इसके आविरिक्त गणराज्य के भूतपूत राष्ट्र पति भी सीनेट के सदस्य होते हैं। इसके आविरिक्त गणराज्य के भूतपूत राष्ट्र पति भी सीनेट के सदस्य होते हैं। इसका कायकाल 6 वय है। निम्न सदन जयांत् वेम्यस आफ डिप्टीज का कायकाल 5 वय होता है। विकिन दोनो सदना को अपने समय के पूत्र भी मय किया जा सकता है। विधि निर्मण के क्षेत्र की सात्रिक सात्र समान है सीनेट को शासन ने विकद्ध अविस्थास का प्रस्ताय करने का लिकार है।

जिस भात को तरफ से उसकी निमुक्ति हो रही हो उसका निवासी एवं उस भान म चार हजार डाकर के मुख्य की स्थायों सम्मत्ति का स्वामी होना चाहिए। उपरोक्त योग ताओं के अत्रगत सीनेटर को जीवन मर के लिए मनोनीत किया जाता है। चीनेट क सदस्या नो संच्छा से पदस्याम का अधिकार है। इसके अतिरिक्त निरत्तर होने बाते होने अथवा निर्धारित योग्यताओं को खोने की जनस्या म सीनेटर को अपना पदस्यान

धीनेट की वतमान सदस्य-सह्या 102 है। विभिन्न प्राप्तों को एयक एक्ट 24 सदस्य भेजने का अधिकार प्राप्त है। स्मरणीय है कि 1867 ई के प्रश्नेक को भीने से सदस्य सह्या 72 निष्टिचक की गयी थी। तीन प्रल प्रत्य के अधीन सीनेट की सदस्य सह्या 72 निष्टिचक की गयी थी। तीन प्रत्य प्रत्या ने प्रश्नेक को 24 सदस्य प्रतिनिधि के इत्य में भेजने का अधिकार प्रदान किया गया था। वनाहा म नवीन प्राप्तों को भावने के उपनिविधित्व की हृष्टि से एक प्राप्त माता निधित्व का शिव्वा से कामता माता प्राप्तों को निविध्य का शिव्वा ते काम्यम न रचा जा सका। सिवधान के स्पष्ट कर दिया गया पा कि एडवड डीप के उपनिवध्य में मिनने पर सीनेट म वे सदस्य उपका प्रतिनिधित्व की गया।। 1871 ई के अधिनिध्य की पटाकर 10-10 सदस्य कर दिया जाया।। 1871 ई के अधिनिध्य होरा कामहा की समद को नवीन प्राप्तों के लिए असे किया गया। इसके अतिरिक्त गवनिव्य कर दिया गया। के लिए 3 से 6 तक समान रूप सं अतिरिक्त सदस्या की नियुक्त का भीने की सीनेट को सीनेट की नियुक्त का अधिकार दिया गया।। इसके अतिरिक्त गवनेत का की लिए 3 से 6 तक समान रूप सं अतिरिक्त सदस्या की नियुक्त का अधि सीनेट की सीनेट की नियुक्त का सीनेट की सीनेट की सीनेट की सीनेट की सीनेट की सिनेट की सीनेट क

सिवधान में सीनेट की शिक्तियों की स्पष्ट ब्याख्या नहीं की गयी है, केवत यही उल्लेख है कि कर एवं ब्यय सम्बंधी विधेषक संवप्रधम कॉम सं समा में ही प्रस्तु किये जोगें। सामाय और नीर विशोध विधेषक संवप्रधम कॉम सं समा में ही प्रस्तु समा के समा के समा में ही शिक्षिय प्राप्त है। सामा य विधेषक प्रथम वार सीनेट को काक्स है। दोनों सदया में गितिर को काक्स के है। दोनों सदया में गितिर को अवस्था में गितिर को अवस्था में गितिर के अवस्था में गितिर के स्वस्थी कर सहती के सत्या से मीनेट में प्रस्तावित से अदस्थी तक की सीनट में बाद कर सकती है। स्पर्णीय है कि गवनर कर सकती क्ष्यवहार में मित्र के कि प्रस्तु के प्रसास के स्वति कर सम्मा के स्वति कर सम्मा के स्वति कर स्वति कर सम्मा के सम्मा के स्वति कर सम्मा के सम्मा के स्वति कर सम्मा के सम्मा के सम्मा के स्वति कर सम्मा के सम्मा के स्वति कर सम्मा के समा के सम्मा के सम्मा के समा के सम्मा के समा के समा

1,

धीनेट ने 1912 हैं य जिन-विशेषक को अस्तीकार किया था। 1923 है एव 1924 ई म धीनेट न कनाडा रेलव के निर्माण सम्त्र भी निर्मयका के प्रस्ताव को अस्त्रीकार किया तथा 1925 ई म होम वैन सम्ब भी निर्मयक को स्वीपित किया था। स्मरणीय है नि 1922 ई हा 1930 ई तक धीनेट म अनुदार दस का बहुमत था। जत इस काल म धीनेट ने वित्तीय भामता म अपने अधिनारो ना प्रदान करने ना त्रयस्त दिया था। निर्वाचन म निर्मी दस न पराजित होन पर सीनेट म जसक प्राम इद्य जवगरा पर नवीत शामा का परशात करत के लिए जपती शक्ति का प्रयोग रिया जाता है। मि प्रमण्डन सानट के प्रति उत्तरदायी न हानर गामन्स समा न प्रति उत्तरवायी हाता है। क्स जनार मित्रमण्डला का निमाण हुआ है जिनम रो रह का काइ भी मुक्ति मात्री नहीं था । 1920 ई क बाद न परिवमण्डल म सीनट ना नकर गर ही सदस्य भैर विचानीय मात्री होता रहा है। गर्धावय

गीनट को सदरवता त्यीय गवाजा क प्रतिकत एव उपहार-स्वरूप प्राय पदा-यस्या म प्राप्त हा है ह इसम नियुक्तियाँ दलीय आधार पर यी जाती है । यदि उदारद शिय मित्रम इन दास्ति म होता है तो वह उदारदत्तीय सदस्या नी ही नियमित बरता है। इनका यह दाव है कि यदि एक दल बहुत समय तक पदास्त रहता है ता मी द र उमी दल का बहमत हो जाता है और दन के निम्न सदन म हार जान पर भी सीनद म उपना बहमत बता रहता ?। मीनट दलीय आधार पर ही निणय परती है अत यजादा की सीधट को यह सम्मान प्राप्त नहीं है जा वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्या की पत्रा का स्वामाधिक रूप म प्राप्त होना चाहिए ।

सामाजिक विधेवका व प्रति सीनेट के हप्टिकीण को बहुपा प्रतिक्रियायादी यह यर तीत्र आलाचना की जाती है। केनेडी के अनुसार बनाडा की सीनट खुनाधिक मुच हा पूरी है और वह उपहास-पूरत वातावरण तथा निष्कत कुचन्न सं मिरी हुई है। " सीनट द्वारा दितीय सदा क मदाधनारमक कतव्य ही मली-मांति सम्पादित किये जात हैं। यह संघीय सिद्धा त यी भी रक्षा नहीं कर संकी है। सीनट म संघ के घटका यो अगमान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसकी असप्तता वा प्रधान कारण यह है कि इसर माध्यम से असम्मय का सम्भय बनान का प्रयत्न किया गया था। लॉउसमा की मांति सीनट प' सदस्या को जीवन भर के लिए चनन की योजना थी। अत मनोनयन की पद्धति का अपनाया गया । इसके अतिरिक्त सीनट म संधीय सिद्धात को मा यता दने का प्रमत्न क्या गया है। यह के दीय सत्ता द्वारा निर्वाचन की प्रणाली के बिल-कुल विपरीत है। "

आस्ट्रेलिया का द्वितीय सदन-सीनेट

आम्ट्रेलिया का यतमान सविधान (कामनवेल्य ऑफ आस्ट्रेलिया अधिनियम, 1900 ई) 1 जनवरी, 1901 ई से लागू हुआ। इस सविधान द्वारा द्विसद-नीय व्यवस्थापिका का निर्माण किया गया है । प्रतिनिधि सदन (House of Represen tatives) निम्न सदन है । सीनट (Senate) उच्च सदन है । सीनेट का सगठन

सीनेट म प्रारम्भ में केवल 36 सदस्य थे। आस्ट्रेलिया के सघ की 6 घटक

Strong, C F op cut, p 203

³⁷ "The Canadian Senate has become almost a cipher surrour with devisive state and the trappings of impotence '--38

इकाइया—राज्या—को सीनट म समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है और प्रत्वेक राज्य 6 सदस्य भेजता था। 1948 ई. म प्रत्यक राज्य को 10 सदस्य भेजने का निर्म कार दिया गया है। अत अब सीनेट की कुल सदस्य सस्या 60 है। इसी वप सीनेट के निर्वाचन व निए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणानी का मूत्रपात किया गया था। अत सीनेट क सदस्य प्रत्येक राज्य की जनता हारा एकल निर्वाचन क्षेत्र क रूप म वयस्क मताधिकार कं शोधार पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार निर्वा चित किय जात है। आस्ट्रिल्या की ससद को सीनेट के सदस्या की सदया की पटाने-बढान का अधिकार है लेकिन किसी राज्य को सीनेट म समान प्रतिनिधित्व से विचत नहीं किया जा सकता।

सीनेट का कायबास 6 वप है। आधे सदस्य प्रति तीन वप बाद अवकास यहण कर लेत है। आस्ट्रनियन सीनेट अमेरिकी सीनेट की मीति स्थापी सदन नहीं है। दीना सदना म गतिरोध उत्पन्न होने की अवस्था म गवनर जनरल दोनो सदनो को विषटित कर देता है तथा दोनो सदनों कं नवीन निर्वाचन होत हैं। वेकिन ऐसा अभी तक ऐवल दो बार 1914 ई एवं 1951 ई म ही हुवा है। सीनेट की शवितयाँ

सीनेट को निम्न सदन—श्रीतिनिधि सदन—के समान ही विधायी दानितयाँ प्राप्त हैं। विक्त विषयक को प्रतिनिधि सदन म ही सबप्रथम प्रस्तुत किया जाता है। सीनेट की वित्त विधेयको को सलीधित करने का अधिकार नहीं है वह क्वल जहें अस्वीकार कर सकती है। तेप सभी विभेषक दोनो भ से किसी भी सदन म सवप्रथम प्रस्तुत किये जा सकत है एवं बोनों सदना झरा पारित होने के पहचात ही विधि बन सकते हैं। दोनो सबनो म उत्पन मतभेद को हुर करने के विए सविधान म व्यवस्था की गयी है। यदि प्रतिनिधि सदन द्वारा पारित होने के तीन माह के भीतर किसी विधेयक की सीनेट डारा अस्वीष्टत किया जाता है तो गवनर जनरस दोना सदनो को विपटित करके नवीन चुनाव के आवेश दे सकता है। यदि फिर भी नव निर्वाचित सदस्यों मं मतभेद रहते हैं तो दोनो सदनों के संयुक्त अधिवेदान म स्पष्ट बहुमत से विधेषक के पारित हीने पर गवनर जनरल उसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकता है।

ष्ट्राम क बहुतार अमरिकन सीनेट की माति बास्ट्रेनियन सीनेट भी सधीय विचार ना प्रतिनिधित्व करती हैं। स्मरणीय हैं कि सविधान के निर्माण के समय वितीय सदन क लिए राज्य सदम (House of States) और राज्य समा (States Assembly) नाम मुक्ताय गये वे और वह राज्यों क विरोध के विवरीत सभी छोटे राज्या को सीनेट म समान प्रतिनिधित्व दिया गया।

वया आस्टेलिया की सीनेट द्वितीय सदन के कतव्यों ने निर्वाह म सफल

[&]quot;CF op cut p 214

सिधान निर्माताओं न सीनेट से निम्न दो कतव्यों को अपेक्षा की यो। प्रथम, सदीधन सदन के कतव्या अर्थात् निम्न सदन के कार्यों को सद्योधित करने की सीनेट से आशा की गयी थी। सीनेट इस कतव्य को स्तीधजनक ढण से सम्पादित करने म असफल रही है। दितिथ कतव्य राज्यों के हितों की रक्षा करना था। इतम भी सीनेट असफल रही है। स्त्राय के अनुसार "व्यवहार म सीनेट भी निम्न सदन नी माति ही राजनीतिक दो को आधार पर विमाजित रहती है। सभी प्रक्लो पर राज्यों के हिता की इंटिंट से नहीं अपितु दलीय है कि सीनेट भी निम्न सदन नी माति ही राजनीतिक देशों के सीनेट अर्था के लिता की ही आता है। अत जो दल निरत्य दो चुनावों में विजयी हो जाता है उसका सीनेट पर नियानण स्थापित हो जाता है। अत जो दल निरत्य दो चुनावों में विजयी हो जाता है उसका सीनेट पर नियानण स्थापित हो जाता है। अत को इस के विचारों के सित्य की सामयन होता है। उनके अनुसार सीनेट द्वारा राज्यों के हिता की रक्षा नहीं की यथी है। ऐसे बहुत ही कम प्रकल उसके समक्ष आये हैं भोरिकन सीनेट को नियुक्ति एव विदेश-नीति पर नियानण जैसे विशेष करूव इस सदन को प्रास्त नहीं हैं। अत आस्ट्रेलिया की सीनेट अमेरिकी सीनेट की नकल होते हुए भी उसकी निम्म सेणों की प्रतिविध प्रमाणित हुई है। धि कुछ विचारकों ने सीनेट को समायन करने का प्रीतिविध प्रमाणित हुई है। धि कुछ विचारकों ने सीनेट को समायन करने का भी सुकाव दिया है।

सोवियत रूस का द्वितीय सदन-राष्ट्रजातीय सोवियत

स्टालिन सविधान (1936 ई) द्वारा द्विसनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गमी है। सुप्रीम सोवियत रूस की सधीय व्यवस्थापिका है। सुप्रीम सोवियत के दो सदन है—सप सोवियत (Soviet of the Union) निम्म सदन एव राष्ट्रजातीय सोवियत (Soviet of Nationalities) द्वितीय सदन है। प्रथम सदन प्रत्यक्षत जनता द्वारा निविध्यत होता है।

सोवियत रूस बहुराष्ट्र जातियों (Multi Nationalities) का देश है। इ हे दितीय सदन मं प्रतिनिधित्व दिया गया है। राष्ट्रजातीय सोवियत के लिए सोवियत रूस के विभिन्न घटका—स्था गणराज्या, स्वशासित गणराज्या एवं क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय केत्रों—को जनता द्वारा प्रतिनिधि (डिप्टीच) चुन कर भेजे जाते हैं। प्रत्यक्त सम गणराज्य 25 सदस्य, स्वशासित गणराज्य 11 सदस्य, स्वशासित क्षेत्र 5 सदस्य एवं प्रति राष्ट्रीय क्षेत्र 1 सदस्य निविचित करके भेजता है। इसकी कुल सदस्य सक्या कि 1 दितीय सदन सोवियत रूस की सभी राष्ट्र जातिया के हिता का प्रतिनिधित्व करता है।

दोनो सदनो का कायकाल 4 वप है। दोनो ही सदनो के अधिवेशन एक साथ होते हैं और एक साथ ही समाग्त होते हैं। प्रशासन, वित्त एव विधि निर्माण के सम्ब भ म दोनो की शक्तिया समान होती है। दोनो ही सदनो द्वारा विधेयक पारित होने पर विभि वनता है। दोना सदना में विवाद उत्पन होने की अवस्था में वह दोनो सदना की एक समभौता समिति के समक्ष रखा जाता है। यदि यह समिति भी विवाद को

⁴⁰ Strong, C F op cit, p 215 41 Bryce Modern Democracies, Vol II, p 204

इनाइयो—राज्या—को सीनट म समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है और प्रत्यक राज्य 6 सदस्य भेजता था। 1948 ई म मत्यक राज्य को 10 सदस्य भेजने का बांध नार दिया गया है। अत अब सीनट भी जुल सदस्य सस्या 60 है। इसी वप सीनेट कं निर्वाचन व लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वा सूत्रपात क्या गया पा। भत सीनेट क सदस्य प्रत्यक राज्य की जनता द्वारा एकल निर्वाचनकात्र क रूप म वयस्य मताधिवार कं जीधार पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कं अनुसार निर्वा-चित निय जात हैं। आस्ट्रेनिया की संसद को धीनट के सदस्या की सहया की पटाने-यवान का अधिकार है लेकिन किसी राज्य को सीनेट म समान प्रतिनिधित्व से बिन्त नहीं भिया जा सकता।

सीनेट का कायकाल 6 वय है। आप सदस्य प्रति तीन वय बाद अवकास पहण कर लेत हैं। आस्ट्रनियन सीनेट अमेरिकी मीनेट की मृति स्थायी सदन नहीं है। दीना सन्ना म गतिरोध उत्पन्न होने की अवस्था म गवनर जनरत दोना सहनो को विषटित कर देता है तथा दोना सदना व नवीन निवाचन होत हैं। लेकिन ऐसा अभी तक पवल दो बार 1914 ई एवं 1951 ई म ही हुआ है। सीनेट की शवितयाँ

धीनेट को निम्न सन्न—प्रतिनिधि सदन—के समान ही विषायी एक्तियाँ प्राप्त हैं। वित्त विषयक को प्रतिनिधि सदन में ही सवप्रथम प्रस्तुत किया जाता है। सीनेट को वित्त विद्ययमा को संयोधित करने का अधिकार नहीं है वह केवल उह अस्वीकार कर सकती है। दोप सभी विधेयक दोनो म स किसी भी सदन म सवमयम प्रस्तुत किये जा सबते हैं एवं बीनों सदना हारा पारित हीने के पश्चात ही विधि बन सबते हैं। दोनो सदना म जत्यन मतभेद को हूर करने हे लिए सित्यान म व्यवस्था की गयी है। यदि प्रतिनिधि सदन हारा पारित होने क तीन माह के भीतर निसी विभेयक को सीनेट द्वारा अस्वीष्ट्रत किया जाता है तो गवन र जनरल दीनो सदनो को विषटित करके नवीन चुनाव के आदश है सकता है। यदि फिर भी नव निवासित मदस्या म मतभेद रहत है तो दोनो सदनो के संयुक्त अधिवेदान म स्पष्ट बहुमत से विभवक के पारित होंने पर गवनर जनरल उसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकता है।

स्त्राम के अनुसार अमरिकन सीनेट की भौति आस्ट्रेलियन भीनेट भी संघीय विचार का मतितिधन करती है। स्मरणीय है कि सविधान के निर्माण के समय हितीय सेवन क लिए राज्य सेवन (House of States) और राज्य समा (States Assembly) ताम सुमाम गम वे और वहें राज्यों के विरोध के विपरीत सभी छोटे राज्या को सीनेट म समान प्रतिनिधित्व दिया गया।

भया आस्ट्रेनिया की सीनेट द्वितीय सदम के क्तब्यों के निर्वाह में सफन 39 Strong C r op cut p 214

1

सविधान निर्माताओं ने सीनेट से निम्न दो कतव्यों की अपेक्षा की थी। प्रथम, सशोधन सदन के कतव्यो अर्थात निम्न सदन के कार्यों को सशोधित करने की सीनेट से आशा की गयी थी। सीनट इस कतव्य को सन्तोपजनक ढग से सम्पादित करने म असफल रही है। द्वितीय कवव्य राज्यों के हिता की रक्षा करना था। इसमें भी सीनेट असफल रही है। स्टाम के अनुसार 'व्यवहार म सीनेट भी निम्न सदन की भाति ही राजनीतिक दला के आधार पर विभाजित रहती है। सभी प्रक्रनी पर राज्यों क हितो की हिष्ट से नहीं अपित दलीय हिष्ट से ही विचार किया जाता है। अत जो दल निरतर दो चनाबों से विजयी हो जाता है उसका सीनेट पर नियानण स्थापित हो जाता है। 40 बाइस के विचारों से भी इसी मत का समयन होता है। उनके अनुसार सीनेट द्वारा राज्या के हिता की रक्षा नहीं की गयी है। ऐसे वहत ही कम प्रश्न उसके अमेरिकन सीनेट को नियक्ति एव विदेश-नीति पर नियं नण जैसे विशेष कतव्य इस सदन की प्राप्त नहीं है । अत आस्ट्रेलिया की सीनेट अमेरिकी सीनेट की नकल होते हुए भी उसकी निम्न श्रेणी की प्रतिलिपि प्रमाणित हुई है । 41 कुछ विचारका ने सीमेट को समाप्त करने का भी सुभाव दिया है।

सोवियत रूस का द्वितीय सदन--राध्टजातीय सोवियत

स्टालिन सविधान (1936 ई) द्वारा द्विसनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गयी है । सुप्रीम सावियत रूस की सधीय "यवस्थापिका है। सुप्रीम सोवियत के दो सदन है—सब सोवियत (Soviet of the Union) निम्न सदन एव राष्ट्रजातीय सोवियत (Soviet of Nationalities) द्वितीय सदन है । प्रयम सदन प्रत्यक्षत जनता द्वारा निर्वाचित होता है।

सोवियत रूस वहराप्ट-जातियो (Multi Nationalities) का देश है। इ.ह दितीय सदन म प्रतिनिधित्व दिया गया है। राष्ट्रजातीय सोवियत के लिए सोवि-यत रूस के विभिन्न घटका-सघ गणराज्या, स्वशासित गणराज्या एव क्षेत्रा तथा राप्ट्रीय क्षेत्रो-की जनता द्वारा प्रतिनिधि (डिप्टीज) चुन कर भेजे जाते हैं। प्रत्यक सघ गणराज्य 25 सदस्य, स्वशासित गणराज्य 11 सदस्य स्वशासित क्षेत्र 5 सदस्य एव प्रति राप्टीय क्षेत्र 1 सदस्य निर्वाचित करके भेजता है। इसकी कल सदस्य सस्या 640 है। द्वितीय सदन सोवियस रूस की सभी राष्ट्र जातियों के हिता का प्रतिनिधित्व करता है।

दोनों सदनों का कायकाल 4 बप है। दोनों ही सदनों के अधिवेशन एक साथ होते है और एक साथ ही समाप्त होते है। प्रशासन, बित्त एव विधि निर्भाण के सम्बाध म दोनो की शक्तिया समान होती है। दोना ही सदनो द्वारा विधेयक पारित होने पर विधि बनता है। दोना सदनों में विवाद उत्पान होने की अवस्था म वह दोनों सदना का एक समझौता समिति के समझ रखा जाता है। यदि यह समिति मी विवाद को

⁴⁰ Strong C F op cit, p 215 41 Bryce Modern Democracies, Vol II, p 204

हल गरा म असपार रहती है ता मुत्रीम साविषत्त ही प्रमाडियम दाना सदना का विपाटत करा नवीर तिसारत का आदन दती है।

राष्ट्रवासीय सावियत ना निम्न सदा—सच गाविया—न सपुरः अपियान म प्रेसीदियम एव मन्त्रिमण्डल न गदस्या नो निवाचित करन ना अपिनार है। इसर अतिरिक्त योगा सदमा ना गर्वोच्य यायातय एव विशेष यायातया । सदस्या की नियाचित रूरन एय प्रारमुहेटर जनहरू की नियुक्ति करन ना नी अधिकार प्राप्त है।

स्विस द्वितीय सदन-राज्य-परिपद

स्विटजरसण्ड सपीय दस है एवं यहाँ ने सपीय व्यवस्थापिका (Federal Assembly) डिमब्सारसन है। प्रथम सदन नो राष्ट्रीय समा (National Council) य डितीय सदन को राज्य परिचय (Council of States) बहुत हैं।

राज्य परिषद का सगठन

स्ट्राग म अनुसार स्विस राज्य-परिषद कवत एक प्रथ म हो सपुक्त राज्य अव-रिता एव आस्ट्रेनिया क अनुरूप है। स्वित परिषद मी इकाइयाँ—एका —को राज्य परिषद म समान प्रतिनिधित्य प्राप्त है। मैं उरूप क्षण्य म प्रत्येन पूप कच्छन का दो सदस्य एव अद्ध क्षण्यन को एक सदस्य नेजन गा अधिनार है। राज्य-परिषद की इक्त सदस्य-सस्या 44 है। सभी केण्टना म परिषद के सहस्या में निवायन की कोई एक समान विधि नहीं है। प्रत्येक वेण्टन म निवायन की विधि जिन हाती है। 21 केण्टना म राज्य परिषद के सहस्य प्रत्यक्ष चीत से जनसा द्वारा या जन समाना द्वारा निवायित होत है एव 4 वेण्टना म स्वयदस्यापिनाआ द्वारा धून जाते हैं। वरिषद ने सदस्या का मणकात 1 से 4 वप तक हाता है।

राज्य परिषद की शक्तियाँ

योना सबना की चित्रमां समान हैं। विभेयक क्सी भी सबन म प्रस्तुत क्या जा सकता है। सधीय परिपद (कायपातिका) के सदस्य दोना सबना के प्रति उत्तर-दायी होत हैं। ये दोना सबना के अध्यक्षानों म भाग लेत हैं, परन्तु किसी भी सबन म मत नहीं देते। दोनों सबना के अध्यक्षा द्वारा यह निश्य किया जाता है कि सबस के स्वत्येक सम कीन स विभेयक किस मतन म प्रस्तुत किय कार्य। कुछ कार्यों जहें सिर्ध्य की सदस्या, परिषद के अध्यक्षा, सधीय "यायालय के सदस्या सधीय सनाध्यक्ष के निर्वाचन एव समादान, आदि के तिए दोनों सदना क संयुक्त अधिवंधन आहुत किये जात हैं।

सिवधान द्वारा दाना सदना को समान झित्तवों प्रदान की गयी है परन्तु व्यव-हार म राष्ट्रीय सभा का महत्व अधिक है एव वह अधिक झित्तवाली है। इसका परण यह है कि प्रत्यक्ष रीति से निवाधित सदन की त्रोकत न म उपक्षा बरना कठिन होता है। राष्ट्रीय सभा जनता का सदन है जबकि राज्य-परिषद केष्टना का सदन है।

Strong C F op at p 215

सी एक स्ट्राग के अनुसार "स्विस व्यवस्थापिना भी स्विस कायपालिका की माति अनोखी है। विश्व का यही एकमान ऐसा विधानमण्डल है जिसके उच्च सदन के काय निम्न सदन स किसी प्रकार भी चिन नहीं हैं। "अ इसके अतिरिक्त, स्ट्राग की यह भी धारणा है कि स्विस राज्य परिपद वस्तुत सामा य अर्थों मे द्वितीय या संधीय सदन (Federal Chamber) नहीं है। यदि यह शुद्ध संधीय सदन होता तो उसका आश्विक कत्वय यह होता कि वह राज्या के हितो की उस सत्ता से रक्षा करे जिसके पक्ष में राज्यों ने अपनी सप्रमुता का परित्याग किया है और यदि यह सामा य द्वितीय सदन होता तो उसको निश्विच कप से संशोधन सम्बन्धी कत्वव्य या निष्धाधिकार प्राप्त होते। "अ कुछ कतव्य दोनो सदन अपने संधुक्त अधिवेशन में एक साथ पूरा करते हैं असे कि संधीय परिपद (कायपालिका) के सदस्या, संधीय सर्वोच्च यायालय एव संधीय बीमा यायालय के बायापिशा, अध्यक्षी एव उपाच्छा को निवाचन 16

भारतीय गणराज्य का वितीय सदत-राज्यसभा

भारतीय गणराज्य का द्वितीय सदन अधिकाशत निर्वाधित एवं जशत मनो नीत सदन है। अत स्ट्रांग के दितीय सदनों के वर्गीकरण के अनुसार इस आशिक रूप से निवासित द्वितीय सदन की श्रेणी में रखना ही उचित है।

राज्यसभा का सगठन

मारतीय ससद का स्वरूप द्विसदारासक है। निम्म सदन लोकसमा (House of People) जनता द्वारा सावमीम वयस्क मताधिकार के आवार पर निर्वाचित सदन है। द्वितीय सदन राज्यसमा (Council of States) अप्रत्यक्ष रीति स निर्वाचित सदन है। इसके 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला एव समाज सेवाओं के सेवों म से मनोनीत किये जाते हे। "यह सयीय सिद्धा त के विरुद्ध है। इस सदन की अधिकतम सदया 250 निश्चित की गयी है जो लोकसमा की वतमान सस्या के आपि से भी कम है। राज्यसमा की अधिकतम सदस्य स्वाया 240 है। 219 राज्यों के प्रतिनिधि एव 9 के द्व सासित सेनों के प्रतिनिधि तथा 12 मनोनीत सदस्य होते है। राज्यसमा के अदिनिधि तथा 12 मनोनीत सदस्य होते है। राज्यसमा के सदस्यों को अप्रत्यक्ष रीति से राज्य की विधानसमा के निर्वाचित सदस्य द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकत सक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इस एक्ल प्रणाली म मतदाता केवल एक प्रत्याशी की ही मतदेता है कि किन की नमश द्वितीय एव व्य य सदे सी व्यक्तकरूप के अधिकार होता है। इस स्वतस्य के नदमन मतदाता का मत व्यय नहीं जाता है। सवधार के ज्ञासर के द्वारा के द्वारा के द्वारा के दवनन मतदाता का मत व्यय नहीं जाता है। सवधार के ज्ञासर के द्वारा के दवनन मतदाता का मत व्यय नहीं जाता है। सवधार के ज्ञासर के द्वारा के दवनन मतदाता का मत व्यय नहीं जाता है। सवधार के ज्ञासर के द्वारा के दवनन मतदाता का मत व्यय नहीं जाता है। सवधार के ज्ञासर के द्वारा के दवनन मतदाता का मत व्यय नहीं जाता है। सवधार के ज्ञासर के द्वारा के दवनन मतदाता का मत व्यय नहीं जाता है। सवधार के ज्ञासर के द्वारा के दवनन सतदाता का स्व

^{43 &#}x27;The Swiss legislature, like the Swiss Executive, is unique It is the only legislature in the world the functions of whose upper House are in no way differentiated from those of the lower —Strong, C F op att, p 216

⁴⁵ Hans Huber How Switzerland is Governed, 1946, p 44

⁴⁶ अनुच्छेद 80 (अ)।

य न्या न प्रतिनिधिया न निर्वारत की शीत गमद का निपारित करा का अधिकार माचा है।

राज्यमना एक स्यायी गदा है। इमा एक तिहाई सम्स्य प्रति ही वय परवात अवशास प्रदूष हरते हैं। राज्यसमा की मनस्पता की निम्न योग्यताएँ हैं—(1) मार वीय गमिरित हो (2) 30 वर्ष से बम आंद्र का न हो, एव (3) लोहमना न लिए िवाहित होते की बोग्यता रगता हो। यह तीतरी ध्यवस्था कम्मू उत्मीर राज्य क स दम म लागू नहीं होती। राज्यसभा को शक्तियाँ

राज्यसमा को गतिको जिम्मवत् हैं —

(1) विषायो श्रान्तियां—गर विसीय विधेवना को सवप्रथम राज्यसना मंत्री प्रस्तुत विया वा सबता है तथा सारतमा म प्रस्तावित एव पास्ति विधयको का राज्य-समा द्वारा पारित होना वावस्यक है। राज्यसमा को नाकसमा द्वारा पारित विभेयका को अस्वीकार एवं संशोधित करन का अधिकार त्राप्त है। साकसना द्वारा प्रस्तायित सतीयन च अम्बोनार होन तो अवस्या म उत्पन्न पतिरोध ना दोना सस्ता क संयुक्त अपिवसन म ही निषय होता है। सिकन राज्यसमा हिसी भी विषयक को स्थानी हर से पारित हाने से नहीं रोड़ सेवती। बहु अधिक से अधिक पर वितीय विध्यक व पारित होन म 6 माह ना विसम्ब वर सक्सी है।

(2) वित्तीय शित्वयां—वित्तीय क्षेत्र म राज्यतमा की पक्तियां कम हैं। वित विभेषक संवप्तयम लोकसमा म ही प्रस्तुत निया जाता है। लोकसमा द्वारा पास्ति वित्तं विषयक ही राज्यसमा व समक्ष प्रस्तुतं किया बाता है। राज्यसमा वित्तं विषयक को अधिक सं अधिक 14 दिन के लिए रोक सकती है। राज्यसमा की विकारिया को त्वीकारता या अस्वीकारता लोगसमा पर तिमर है। यदि राज्यसमा भी सिकारिस का त्याराच्या वा अरवाकाराज कार कथा पर एकर हर बाब राज्यक्या था (क्यार लोकसमा को माय नहीं होती तो यूत रूप म बित्त बिपयक पास्ति माना जाता है।

ा जा ना च नहा हमा हा जेंग हुन न निवास निवस के प्रति स्वत्सारी होता है [अनुक्छत 75 (3)] । अतः राज्यसमा म पराजित होने पर उसे त्यायपत्र दने की ्रित के किन्त राज्यसमा मित्रमण्डल को प्रस्त प्रथमित पायसमा मित्रमण्डल को प्रस्त प्रथमित स्थान भावत्वकाता गर्ध र १ १०१२मा अनेक प्रकार स प्रमावित करती है। राज्यसमा के पात का जारावाम करण ज के जाराज के जाराज के जारावा के विचार के विचार को सदन में उपस्थित होन र अपने वचार में उत्तर वयर १ एत १८ भाग गा भा वया में विश्व हैं ते किन ऐसे सभी जी सदन के सबस्य नहीं होते. सतदात में माय नहीं ले सकते (अनुच्छे 88)।

प्रमाणिक गरितयाँ स्वयानिक संबोधन का प्रस्तात सवप्रथम किसी सदन म भी प्रस्तुत किया जा सकता है (अनुच्छेद 368)। सवमानिक संशोधन के समस्त प्रया न ना जापुर क्या का प्रकार है (अप्रकार अवन विवास के समापान के प्रवास के समापान होंगा अवस्थिक हैं। विवास के समापान दोना सदना की सयुक्त बैठक में होता है।

(5) अप फतब्य---उपरोक्त कतव्या के अतिरिक्त राज्यसमा के अप कतव्य तिम्न है राज्यसमा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन म भाग लेते है। 17 राष्ट्र पति पर महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसमा म प्रस्तुत क्या जा सकता है एवं कुल सदस्या के दो तिहाई बहमत से प्रस्ताव का पारित होना जावस्थक है। दूसरा सदन अर्थात् लाकसमा या उसके द्वारा नियुक्त "यायाधिकरण महानियोग की जाच करता है। यदि लोकसमा में महामियोग का प्रस्ताव सवप्रथम प्रस्तावित किया जाता है तो राज्यसमा या उसके द्वारा नियुक्त यायाधिकरण को उसकी जाँच करने का अधिकार होता है। 48 दा माह से अधिक समय के लिए सकटकातीन घोपणा को कायम रखन के लिए राज्य समा की स्वीकृति आवश्यक है। " राज्यसमा प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी मी विषय को राज्डीय महत्व का घोषित कर सकती है। इससे ससद को उस विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि बनान का अधिकार प्राप्त हो जाता है। " लेकिन यह प्रस्ताव केवल 1 बप तक ही प्रमावकारी रहता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन म लोकसमा के साय राज्यसमा क सदस्य भी भाग लेते हैं। शाज्यसमा द्वारा उपराष्ट्रपति के पदच्युत सम्बंधी प्रस्ताव को पारित करने एवं उसका लोकसमा द्वारा समयन किय जाने पर उपराध्यपित को उसके पद से प्रयक्त किया जा सकता है। ² सर्वोच्च यागालय एव उच्च यायालया क यायाधीशा. मुख्य चनाव आयुक्त, कॉम्पटोलर एव आहीटर जनरल को उनक पदो स दोना सदना द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही हटाया जा सकता है 168 समीक्षा

राज्यसमा म राज्या को जनसंख्या के आधार वर प्रतिनिश्दिल दिया गया है। अमेरिका, स्विद्णराज्यक, आस्ट्रेलिया की भाति तथ के घटको— राज्या— को इस दा म सामान प्रतिनिधित्व प्राप्त नही है। वित्तीय क्षेत्र म राज्यसमा की शक्तिया अत्यिधक सीमित है। प्रचलित लोकत नीय विक्वास के आधार पर मारत मे जनता के प्रतिनिध्या (लाकसमा) को राज्या के प्रतिनिध्या (राज्यसमा) को अपेक्षा वित्त पर वास्त-विक्त मिम नण प्रदान किया गया है। लॉडसमा को वित्त विधेयक को सद्योधित करने की सांति नहीं है। वह अधिक अधिक उसके पारित होने में एक माह का विलम्ब कर सकता है। मारतीय राज्यसमा को वित्त-विधेयको में सद्योधन प्रस्तावित करने का स्वामन हो मारतीय राज्यसमा उसे मानने या न मानने के लिए स्वतन है। राज्य

⁴⁷ अनुच्छेद 55 (2) (व) १

⁴⁸ अनुच्छेद 61 ।

⁴⁹ अनुच्छेद 352 (2) (c), 356 (c) एव 360 (2)। 50 जनुच्छेद 249।

⁵¹ अनुच्छेद 66 (1)।

⁵² अनुच्छेद 67 (ख) ।

⁵³ अनुच्छेद 124 (4) एव 217।

समा जित्त-विवेयक के पारित होने में नेवल 14 दिन का विलम्ब कर मनती है जब कि अमेरिकी सीनेट का जित्त-विपेयकों में सशोधन करने की व्यापक शक्तिया प्राप्त हैं। व्यवहार में सीनेट को जितीय क्षेत्र में प्रतिनिधि सदन से भी अधिक 'गक्तिया प्राप्त हैं। व्यवहार में सीनेट को जितीय क्षेत्र में प्रतिनिधि सदन से भी अधिक 'गक्तिया प्राप्त है। स्पट है कि विलोध मामला में मारतीय राज्यसमा को स्थित लोकममा में निम्न है। लेकिन दोना ही देशों में इगकैंग्ड नी तरह जिता विषेयक निम्न सदनों में ही प्रस्तावित शोते हैं।

भैर विशोध विधेयकां कं सम्बाध म दोनो सदनो की शक्तिया समान है। सर दीय अधिनियम 1949 ई के अधीन ब्रिटिश कामस्य ममा निश्चित पद्धित का अनु गमन करने सभी मामलो म लॉडममा का अनिक्रमण कर मकती है और यदि चाह तो अनेल ही विधि निर्माण कर नकती है लेकिन विशोध क्षेत्र का शोडकर श्रीप समी विषया म भारतीय लोकम्मा पाज्यसमा को त्योका नहीं कर सन्दी।

राज्यसमा का स्थित तृतीय फ्रेंच गणराज्य की गणराज्य परिपद (Council of States) जैसी हम भी नहीं है। यह कनाड़ा की सोनेट की माति भी नहीं है जो प्रीप्तता म पारित अवाक्षनीय विध्यका पर बीच्च प्रतिबन्ध रजान म असमय ही और सवीपन सम्बन्ध दिखिलों को भी ठीक प्रकार म मन्यादित न कर पाती है।

लोकसभा एव राज्यसभा में सम्बाध

लोकसमा की तुलता में राज्यसमा की स्थित विधिक हाँद से निक्त है। फिर मी राज्यसमा एवं लोकसमा में विवाद उत्तर न हुए है। मौरित जास (Morris John) के अनुसार बाता सदना म अल्प्यता करता महिला हो। यदी पी एवं राज्यसमा ने लोकसमा सं प्रतिस्था करता प्रारम्भ कर दिया था। लोकममा हारा राज्यसमा के इस आवरण की तीज आलोबना एवं प्रतिवाद तिया या। लोकममा हारा राज्यसमा के इस आवरण की तीज आलोबना एवं प्रतिवाद तिया गया है। ऐसा अवसर सवप्रथम अप्रल 1953 ई म उस समय उत्तर हुना या जबकि लोकसमा हारा पारित आयकर (सम्राधन) विधेयक 1952 ई पर राज्यसमा विवार कर ही थी। इम अवसर पर राज्यसमा न प्रत्ताव पारित करके विधि मन्त्री प्री विद्यास को जो सदन वे सदस्य थे, लोकसमा म आय-कर विध्यक मम्बर्धी प्रतिवास को जो सदन वे सदस्य थे, लोकसमा म आय-कर विध्यक मम्बर्धी प्राति को दूर करत हेतु जाने से रोक लिया। इपर लोकसमा ने भी विद्यास को सदर म उपस्थित होने ना आन्ध दिया। लोकसमा के सदस्या त राज्यसमा न प्रत्ताव की देशानिकता क प्रति राजपूण आपरित करने हुए यह वहा नि मन्त्रीमण ताकसमा के प्रति उत्तरदायो होते हैं। प्रधानमंत्री धी नहरू क सामध्य हम्तरहेप से स्थिति विगवत स्वा गयी।

जनवरी 1953 ई म दोना मदना क मध्य सथय का पुन अवसर एस'न हो गमा। राज्यसमा द्वारा मावजनिक लेखा-समिनि (Public Accounts Committee) म सम्बन्धित एन प्रस्ताव कोनसमा वे समक्ष उपस्थित किया गया था। इसम यह मुक्तव दिया गया था कि या तो राज्यसमा की अपनी लेखा समिति हा अथवा लानसमा को बन्मान संदान्तिमिति व राज्यसमा की ने महस्या को सिमितिन करने उस दोना सदनों को एक सयुक्त लेखा समिति म परिवर्षित कर दिया जाय। सावजनिक लेखासमिति को यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं ये क्योंकि दोनों ही विकल्प सिवान म निहित
चिद्धा तो के विपरीत थे। सम्मवत यह बात यही ममाप्त हो जाती परन्तु प्रधानमानी
ने लोकसमा म एक प्रस्ताव रखा कि राज्यसमा को लोकसमा की लेखा समिति म
भाग लेने के लिए 7 सदस्य मनोनीत करने के लिए कहा जाय। इस प्रस्ताव ने विवाद
को मदका दिया। प्रधानमानी का उद्देश्य इस प्रस्ताव के द्वारा समुक्त लेखा समिति का
निर्माण या लोकसमा की वित्तीय शानितया को सीमित करना नहीं था। प्रधानमानी
सारा यह आस्वासन दिये जाने पर कि लेखा-समिति लोकसमा की ही समिति रहेगी,
उनके द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव पारित हो सका। इसी प्रकार की कठिनाइया समुक्त
समितियों के गठन को लेकर भी उत्पन्त हुई थी।

ततीय विवाद चटर्जी घटना (1954 ई) स सम्बन्धित है। लोकसमा के सदस्य श्री एन सी चटर्जी ने एक सावजनिक मापण म यह कहा कि वरिष्ठा का निराय (राज्यसमा) हुष्ट बालको के समूह की माति अनुत्तरदायी उग से आवरण करता है। उनके यह राज्य विवाद का विषय वन गये। राज्यसमा मे विश्वेपाधिकार का श्रवर उठामा गया और उसके अध्यक्ष ने सचिव को श्री चट्यों के मापण की सत्यता की जांच करने का जावेश दिया। नाक्समा के सबस्यों ने सचिव डारा यत्र लिखने पर आपत्ति की। स्पीकर न इस सम्बन्ध में निषय देते हुए कहा कि सचिव का पर एक जादेश-पर हु एवं उहीने मुक्काव विया कि इस विवाद तथा ऐसे मामला में सामाच प्रक्रिया के प्रदन पर दोना सदना की विश्वेपाधिकार समितिया समुक्त अभिवेदान मं विचार करे। राज्यसमा इस वात पर सहमत हा गयी और अन्तत मामला समाप्त हो गया।

इन विवादों के कारण राज्यसमा की उपयोगिता विवाद का विषय बन गया। अमेल 1954 ई म लोकसमा में निजी प्रस्ताव द्वारा राज्यसमा को शीझ ही भग करने की माग की गयी। वामपक्षी एवं कामेंस के कुछ सदस्यों ने राज्यसमा को प्रति-नियाबादी तत्वां के मुद्ध गढ एवं जनता को आवाज की उपेक्षा करने वाले सदद की सक्षा दी थी। कुछ सदस्यों ने उसवा कायम रचने की सक्षाह दी परातु उसकी निर्वाचन पदित मंगिरवलन का परामश दिया। सासन का मत्र व्यक्ति निर्वाच प्रतिक्ति का परामश दिया। सासन का मत्र व्यक्ति निकासमा की उप प्राणिता के सम्बन्ध म इतने अस्य समय म काई निषय देना कठिन है।

प्रस्त यह है कि स्वा राज्यसमा प्रभावसाली द्वितीय सदन एवं संघीय सदन के हप में राज्या के हिता एवं उनने सरकातापूवक काय कर सका है ? संघीय सदन के हप में राज्या के हिता एवं उनने सरकाण भी आधा राज्यसमा से पूण नहीं हुँ है। इसका मुख्य कारण यह है कि राज्यसमा एवं लोक्समा का दलीय स्वरूप काम वढ एक सा ही होता है। प्रारम्भिकवर्षा में दाता सदना में एक ही दल का प्राधा य रहा। राज्यसमा में भी अविकाण सदस्य काँग्रेस दन के ही वे। द्वितीय सदन के रूप में दायिख पूर्वि की आधा से ही सविधान-निर्माताओं व राज्यसमा की स्वापना की थी। सविधान सम्म के प्रारम्भ में एक-

सदनीय व्यवस्था की स्थापना के लिए एक सशाधन प्रस्ताव रखा गया था जो पारित नहीं हुआ । श्री गोपालस्वामी आयगर का मत या कि दिसदनीय व्यवस्था के द्वारा ''ए हुणा । जा नाजारमाना जावार जा जा जा जा जा अध्यान जारा जा जारा विद्वान एवं अनुमवी व्यक्तियों के सहयोग का लाम प्राप्त ही सकेगा ¹⁸ थी अनन्तरायनम आयगर ने मी वाद में उच्च सदन की उपयोगिता का समयन करते हुए कहा था कि उच्च सदन की स्थापना का लक्ष्य महत्वपूष मामला म उपयुक्त विचार का अवतर प्रदान करना एवं मावावेश में पारित विधियों के निर्माण म विलम्य करना होता है। राज्यसमा क सम्बंध में कुछ तथ्य महत्वपूष्ण एवं रोचक है। राज्यसमा एवं लोकसमा के दलीय स्वरूप म विशेष अन्तर नहीं रहा है। दोनो सदनो की काय पद्धित यूनाधिक एक ती है लेकिन आकार म छोटा होने के कारण लोकसमा की अवेक्षा राज्यसमा म दार विवाद के अधिक स्वत व अवसर होते हैं। राज्यसमा में प्रतिदिन 23 घटे एव नार त्याव के जानक त्याव न जनकर हात है। राज्यकार व नातावा है। राज्यकार में मुक्तवार का पूरा दिन निजी सदस्यों के कार्यों के लिए दिया जाता है। राज्यक्षमा में धासन द्वारा अनेक विधेयको को सवप्रथम प्रत्याचा चार्या प्रवास वार्या ए । पान्य वार्या ए । पान्य वार्या ए । पान्य कुछ सदस्य राज्यसमा स ही निए जात हैं।

परतु राज्यसमा ने प्रमावधाली ढग से संशाधन करने वाले सदन की प्रमिका नहीं निमायी है। 1952 ई में प्रथम सन म 25 विषयकों म से कैवस 1 म सबोपन किया या। यही स्विति अयं अवसरों की है। 1952 57 ई के बीच म मजुत 363 विभेयको म स 201 विभेयक राज्यसमा म प्रस्तुत किय गये थे। इनम से अधिकार विधेयक सामाजिक प्रकृति के थ।

1889 ई म निमित्त भीजी (Meys) सनिधान के अत्वयत जापान म दिसद नीय व्यवस्थापिका की व्यवस्था की गयी थी। उच्च सदन को पीयस सदन (House of Peers) एवं निम्न तेदन को प्रतिनिधि सदन (House of Representa (1903) वहां जाता था। पीयस सदन म 409 सदस्य थ। 20 वप स अधिक जायु के uve) पर्वाणावा पात्रामण प्रवर्ण प्रपट प्राटण प्राटण प्रवर्ण प्रवाणाला प्राटण प्रवर्ण प्रवाणाला प्रविच्या विश्व पोध्यता बात व्यक्ति इसक तहस्य होते थे। निर्वाचित सहस्या का कायकात ? वय वानका वार ज्यान क्यान क्यान प्रवास होता था। इस व्यापक सक्तियाँ प्राप्त थी। बित्त विधेयक प्रतिनिधि सहन म ही सब पाम अस्तुत किय जात थ परन्तु अमस्कि सीनेट की मीति पीयस सन्म को उसम समी धन करन और अस्त्रीकृत करने का अधिकार था। ीप सभी भागता स रोना सदना की सिक्त गमान थी। यह सञ्ज संगठन की हिस्ट स इंगसण्ड की साडसमा क अधिक निनट या । उसी की मीति राजपरिवार के सदस्या एवं अस्य साम तक्यींने सदस्या

दितीय तस्य पुद्ध म मित्र राष्ट्रा व समक्ष जापान न 1945 है म बारम ममपम निया था। अमरिकी प्ररेणा क प्रमस्त्रह्मप् सावत त्रीय बार्ट्सा पर जापान क 54 C. A D Vol IV P 927

वतमान सविधान का निर्माण हुआ जो 3 मई, 1946 ई को लागू हुआ। इस झाति का सविधान (The Peace Constitution) भी कहा जाता है क्योकि इस सविधान द्वारा युद्ध का परित्याग किया गया है। इसमे स्त्रियो के अधिकारो को भी मायता दी गयी।

इस नदीन सिवधान के अन्तमत द्विसदनीय राष्ट्रीय ससद या डाइट (Natio nal Diet) का निर्माण किया गया है। यह राज्य म श्रांत का सर्वोच्च अग है और विधि निर्माण की सत्ता इसमें मिहित है। उच्च सदन को काउ सतर सदन (The House of Councillors) एवं निम्म सदन को प्रतिनिधि सदन की मौति जन-प्रतिनिधियों का निर्वाचित सदन है। इसकी सदस्य सस्या 250 है। इसके सदस्य आतुन्त नहीं होते। 100 काउ सतर निर्वाचित जिता (Districts) से एवं 150 सदस्य प्रीकेचचरी (Prefectures) से चूने जाते है। "अ सदस्या का कायकात 6 वच है। आधे सदस्य प्रति तीन वय पदचात निवाचित होते है। अत यह एक स्थायी सदन है। कोई ध्यक्ति दोनो सदना का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता। प्रतिनिधि सदन के विपटित होने की अवस्था में काउ सतर सदन मी व द हो जाता है परन्तु राष्ट्रीय सकटादस्या में मित्रवल को उसका अधिवेशन आहुत करने का अधिकार है। काउ सतर सदन द्वारा इस दशा में पारित विधेयक अस्थायों होते हैं और डाइट के आगामी अधिवेशन के प्रारम्म होने के 10 दिन के मीतर यदि उनको प्रतिनिधि सदन स्थिकृति प्रदान नहीं करता ते वे स्वत प्रमावहीन हो जात है।

⁵⁵ जापान म निर्वाचन हेतु प्रत्येक प्रोफेनबर (Prefecture)—प्रान्त-एक से लेकर चार जितो तक म विमाजित होता है। टोकियो इस नियम का अपबाद है। उसम 7 जिते हैं।



त्रों ली स्मिथ का मत है कि नार्वे की ससद एक ऐसी एकसदनीय व्यवस्था पिका है जिसम डिसदनवाद के अवधेष प्राप्त हैं।

आयर गणराज्य का द्वितीय सदन

दीधकालीन स्वात य समय के परुषात 1922 ई में आयरलण्ड स्वत न हुआ या लेकिन जलस्टर (Ulster) का प्रदेश ब्रिटेन का ही भाग बना रहा । आयरलैण्ड के रोव माग एव जिटेन के मध्य एक सिल्ब हुई जिसके फलस्वरूप आयरिश स्वतन्त राज्य का जम हुआ। इस सि के डारा आयरलण्ड को सबत ने जनते द्वारा निर्मित की स्थिति प्राप्त हुई। 14 जून, 1937 ई को आयरलण्ड की सबत ने जनता द्वारा निर्मित नवीन सिवधान को स्वीकार किया। आयरिश की स्टेट आयर (Eire) के नाम से जात है। 1936 ई-म आयरलण्ड ने ब्रिटिश सम्राट का नाम सविधान स हटा दिमा तथा गवनर जनरन के पद को समान्त करके राष्ट्रपति की व्यवस्था की। इस प्रकार जायर लण्ड के ब्रिटिश नाजन से सभी सम्याध समान्त हो यये और आयर गणराज्य का जम हआ।

1922 ई के सिवधान म भी द्विसदनीय व्यवस्थापिका थी। प्रथम सदन को प्रतिनिधि सदन (Dail Eireann) एव द्वितीय सदन को सीनेट (Senate) की सज्ञा दी जाती है। 1937 ई के सिवधान में भी इस व्यवस्था को कायम रखा गया।

1937 ई के सिवधान के अधीन आयरलण्ड की सीनेट का आकार 1922 ई जा ही है। बेकिन दोनों के सगठन में अ तर हैं। पहली सीनेट पूणत निर्वाचित मी अविक वतमान सीनेट आधिक रूप से निर्वाचित एत आधिक रूप से मनोनीत है। 1922 ई के सिवधान के अधीन सीनेट के सदस्यों की सख्या 60 थी। उनना कार्यकाल 12 वर्ष था। एक चौथाई सदस्य प्रति तीन यप परवात अवकारा प्रहुण रुद्ध थे। सभी सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्य के आधार पर चुने जात ने। मदस्यता की

योग्यता सम्बाधी की अहताएँ कठोर थी। सविधान के अनुसार केवल वे ही व्यक्ति सदस्य चुन जा समते है जि हाने कि 35 वप की अवस्था प्राप्त कर ती हो तमा विशेष योग्यता रखते हो अथवा राष्ट्र के लिए भीरव ऑक्त किया हो या राष्ट्रीय जीवन क किसी महत्वपूण भाग का प्रतिनिधित्व करता हो। प्रत्यक निवाचन के पूत्र प्रत्याधिया की एक भूची नैयार वी जाती है। इसकी सदस्य सख्या निवाचित सदस्या शी सख्या से तिगुची होती है। इस के बा तिहाई सदस्य निम्न सदन-प्रतिनिधि सदन (Dal Eireana)—हारा एव एक विहाई भीनट हारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निवाचित किये जाते थे। सीनेट के भूतपूत्र या अवकाश प्राप्त सदस्य प्रधानस्पत्री को अपनी उम्मीदवारी की सुचना बेकर अपना नाम इस सुची म जुडवा सकते थे।

सीनेट की यक्तिया अपेक्षाकृत कम थी । विल-विधेयका के सम्बंध म इसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। लॉडसभा की तरह इसे वेवल विलम्बकारी निषेधा-धिकार प्राप्त था।

1937 ई के संविधान द्वारा सीनेट के सगठन म परिवनन किया गया है। 60 सदस्यों म से 11 प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किये जाने हैं तथा सेव 49 सरस्य निर्वा वित होते हैं। 21 वय से अधिक आयु का नामरिक प्रतिनिधि सहन के लिए निर्वा वित होते हैं। 21 वय से अधिक आयु का नामरिक प्रतिनिधि सहन के लिए निर्वा वित होने का अधिकारी होता है। वह सोनेट के लिए मी तरस्य निर्वाचित सरस्य मा स 2 विश्वविद्यालया द्वारा वया एप 47 सरस्य 5 मूर्विद्या (Panels) म से निर्वाचित होते है। अत्येक निर्वाचन के पूत्र 5 मूर्विद्यां (Panels) म से निर्वाचित होते है। अत्येक निर्वाचन के पूत्र 5 मूर्विद्यां (1) सरहित एवं साहित्य, (2) कसा एवं पिछा, (3) कृषि एवं अप दिता, (4) धनिक उद्योगा एवं पालिस्य (बक्ति, बास्नुकत्ता एवं इजीनियरिंग सहित), एवं (5) लोग प्रधानन और सामाजिक संवा—वे केंग्रा सम्बन्धी गठित भी वाली है। इन सुविद्या ग सहस्य अपनुष्य 19 के अधीन विधि द्वारा स्थावसाधिक प्रतिनिधित्य व अनुमार पूने जान में निता, प्रस्था निर्वण्य सम्बन्धी निर्वण वना सन्त हैं।

निम्न सदन द्वारा पारित विधेयना पर सीनेट को 90 दिन वा विलम्बनारी नियेपापिनार प्राप्त है। भीनेट ना बायपालिका पर बाई निम्न पण नहां है। बाय पालिका केवल निम्न मदन के प्रति ही उत्तरदायों है।

युगोस्ताबिया का द्वितीय सदन

यूगास्ताविषा एक संघीय दश है। ह्यांग न अनुमार मुनोस्ताविषा न गंगराज्य का निमान परित्रमी उन पर नहीं हुआ है पर दु फिर जी परिचयी प्रमाय से यह पूर्व रूपन मुक्त भी नहीं है। अंत्र यूगाम्लाविया के नयीय द्वितिय सदत्त के रहका गर्व कार्यों का अञ्च देता के द्वितीय गण्य न साथ तुननासक अध्ययन जिभावन होगा। "

1946 इ. क्रूपास्ताविया र मधाय विकास का मधीय गर्ग का गर्म

राज्य की जनसमा (Peoples' Assembly of the Republic) की सता दी जाती थी। यह द्विसदनीय व्यवस्थापिका थी। निम्न सदन का सथ परिषद (Federal Council) एवं उच्च नदन की राष्ट्रजातीय परिषद (Council of Nationalities) की मता दी गयी। दोना सदना वा कायकाल 4 वय था एवं अधिकार मी समान थे। संधीय परिष्य (तिम्म सदन) को प्रत्यद्वा रीति से प्रति 50 हजार निवासिया के लिए एक प्रतिनिधि के आधार पर चुना जाता था। दितीय सदन (राष्ट्रजातीय परिषद) को विभिन्न परिपदों के नागरिका हारा 30 प्रतिनिधि प्रति स्वायन्त प्रातः, 20 प्रतिनिधि प्रति भारत एवं 15 प्रतिनिधि प्रति स्वायन्त प्रातः, 20 प्रतिनिधि प्रति सात्र एवं 15 प्रतिनिधि प्रति स्वायन्त प्रातः, 20 प्रतिनिधि प्रति स्वायन्त प्रातः, 20 प्रतिनिधि प्रति स्वायन्त प्रातः, वर्षा प्रतिनिधि प्रति स्वायन्त प्रातः, वर्षा प्रतिनिधि प्रति स्वायन्त प्रातः, वर्षा प्रतिनिधि प्रति स्वायन्त प्रातः वर्षा भारति एवं स्वायन्त प्रातः वर्षा भारति स्वायन्त प्रति स्वायन्त प्रातः प्रतिनिधि प्रति स्वायन्त प्रति स्वायन्त प्रति स्वायन्त प्रति स्वायन्त प्रतिनिधि प्रति स्वायन्त प्रति स्वायन्त प्रतिनिधि प्रति स्वायन्त प्रति स्वायन्त प्रतिनिधि प्रति स्वायन्त प्रतिनिधि प्रति स्वायन्ति स्

दोना सदना के सामा यत पृथक अधिवेधन होत थे। यिसेप अवसरा पर विधेष अधिवंधन मी हो सबत थे। जनसभा के समुक्त अधिवेधन म कायपातिका का निर्वाचन एव सविधान म सद्याधन जस महत्वपूष विषया पर विचार-विमद्ध होता था। इन अधि-वेधना म निष्य बहुमत स हात थे। दोना म स किसी भी सदन म विधेयक प्रस्तुत विचा स सकता था। एक सदन म विधेयक प्रतित होन पर यद दूसरा सदन उसे अस्वीकार करता था हो दोना सदना की एक सम वयकारी समिति उस पर विचार करती थी। यदि समिति भी किसी निषय पर नहीं पहुचती थी तो दोना सदना भो विधिटत व रके नवीन निवाचन किये आतं थे।

यूगोस्लाविया म सथवादिया (Federalists) एव एकात्मक शासन के समयका (Unitarianists) म विवाद बहुत पुराना है। 1960 ई म इसके फलस्वरूप नवीन सविधान के नियाण की घोषणा की गयी थी। प्रस्तावित नवीन सविधान की मुख्य विशेषताएँ निम्न है —

- (1) यूगोस्ताविया का नाम सधीय समाजवादी गणराज्य प्रस्तावित किया गया ।
- (2) नवीन विधान का प्रारूप समाज का सविधान था, न कि राज्य का ।
- (2) नवाग विधान का आस्थ पत्ताज का सायपान था, न का राज्य का ।
 (3) सभीय समा के समठन म आमुलबूल संबोधन प्रस्तावित किय गय थे जिससे पूरे सथ में समाजवादी शोकतात्र के विकास को गति प्रदान की जा सके ।

नवीन सविधान के ज तथन सभीय समा (Federal Assembly) के स्वरूप में आमूलकूस परियतन हो गया है। सभीय समा हिसदनारमक न होकर पाच-सदनीय व्यवस्थापिका है। अल इसके सदना को निम्न या उच्च या प्रथम या हितीय सदनों की सज्ञा नहीं दी जा सकती। इसकी कुल सदस्य सस्था 670 है। प्रत्यक सदन म 120 सदस्य होते हैं। पांच सदना के नाम है—(1) सथीय यदन, (2) आधिक सदन, (3) सक्षणिक एव सास्कृतिक सदन, (4) सावजनिक स्वाव्य एव सामाजिक कट्याण सदन, (5) सगठनारमक एव राजनीतिक सदन । इसके अतिरिक्त, सधीय सदन का एक और अग है जिसे राष्ट्रीयताओं या उपराष्ट्रा का सदन कहते हैं। इसकी सदस्य सरया 70 है। 6 गणराज्यो हारा 10 प्रतिनिधि प्रति गणराज्य एव 2 स्वावन प्रातो हारा

5 प्रतिनिधि प्रति प्रान्त के हिसाब से इसम प्रतिनिधि भेजे जाते है।

सधीय सदन के सदस्य अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित होते हैं। अय सदनों के

306 | आधुनिय द्यासनतात्र

सदस्या को अप्रत्यक्ष रोति स सामुदायिक समाजा द्वारा निर्वाचित विया जाता है। सपीय सदन की सदस्यता प्रत्येश नागरिक को निर्वाचित होन पर ही प्राप्त हो सकती है। पिए सभी सदन व्यावसायिक जापार पर मिठत हैं और उसकी सदस्यता के निर्व व्यवसाय विरोप स सम्बद्धित होना आयदयक है। सदना के किसी सदस्य का सपीय विषि क जापीन निर्धारित निर्वाच्या मण्डल व बहुमत स प्रत्यायत्तन सम्मव है। सपीय समा को विसी भी सदस्य का पिपटित करन का अधिकार है। निर्योग निर्वाच्या प्रदूष्ट वित प अ दर हो जाते हैं। सपीय समा का अध्यक्षा ही निर्योग निर्वाच्य की स्थास्या करता है।

अधिकार एव शक्तियां

सपीय सभा दाक्ति का सर्वाच्च अग है। लेक्ति समा को अपन अधिकार एवं राज्या का पालन सिविधान एवं विधिया के अधीन करना पढता है। उसे विधि निमाण, सपीय वार्षिक आयं व्यय एवं विक्तीय विवरण नो स्वीनार करन तथा आन्तरिक एवं वदेशिय नीति को निर्धारित करने का अधिकार है। सपीय नायकारिणी परिपद में अध्यक्ष एवं सदस्या वा निर्धावन करती है। उद्घ पद्धुत करना, गुढ़ को भोषणा एवं दाति के स्थापना, सामाजिक योजनाआ, राजनीतिक अधिकारिया एवं प्रसासनिक भोने का मार्गे का मार्गे का मार्गे का भो के मार्गे का निर्धाल, गणराज्य की सीमाआ म परिवतन, जन्तराष्ट्रीय सिंपयों की सम्बुष्ट एवं सविधान द्वारा निर्धारित अय मामला के वारे म आवश्यक काववाही करना सपीय सभा वा वारित्व है।

सपीय समा का अधिवार क्षेत्र सथ के अधिकार-धेन के अनुरूप है। विस्तृत है। यूपोस्त्वाविया का पाँच सदतीय विधानमण्डल अपनी काय-पद्धति एवं सगठन प्टिंस अनीखा है। राष्ट्रीयताओं के सदन की स्थिति सधीय सदन जसी है।

कुपास्तायको का पास स्वतान विधाननगढन व्यान कार्यक्रित एवं रूपक की इंटिस कानोशा है। राष्ट्रीयवाओं के सदन की स्थित सपीय सदन जसी है। सपीय संदन का यह एक उपाय है। बिना इस उप-सदन की स्थीकृति के सविधान में नोई परिवतन सम्मव नही है। इस व्यवस्था द्वारा यूपोस्ताविया के समाजवादी गण तानीय सविधान से सपीय सविधान की इस मायता को स्थीनगर किया गया है कि सम में घटका का प्रतिनिधित्व करन बाता एक सदन होना चाहिए। एक सीमा तक समान प्रतिनिधित्व की भी मायता दी गयी है।

11

व्यवस्थापिका—प्रथम या निम्न सदन [LEGISLATURE—FIRST OR LOWER CHAMBER]

व्यवस्थापिका का निम्न सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित सदन होता है । यही सत्ता का केन्द्र एव सच्चे जयों में व्यवस्थापिका होती है । इगलैण्ड म ससद का निम्न सदन समस्त व्यावहारिक कार्यों के निए ससद है। नि ही भी दो देशा के निम्न सदनों की स्थिति एक सी नहीं है। पर तु एक समानता सभी म पायी जाती है। सभी निम्न सदन सावभीम मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति में निर्वाचित होते हैं। कायवाल, आकार एवं शक्ति की हिन्द सं प्राय सभी में कुछ न कुछ असमानताएँ हाती है। उदाहरणायं, इगलैण्ड की कॉम स समा का कायकाल 5 वप, अमेरिका के प्रतिनिधि सदन का 2 वप, कनावा की कॉम स समा 5 वप, आस्टे-लिया के प्रतिनिधि सदन का 3 वप, ततीय फच गणराज्य के चेम्बर आफ डिप्टीज का 4 वय, चतुथ गणराज्य को राप्टीय समा (National Assembly) का 5 वय है। सुप्रीम सोवियत का निम्न सदन सब मावियत (Soviet of the Union) 4 वप, भारत की लोकसभा 5 वप एव स्विटजरलैण्ड की राष्ट्रीय परिषद 4 वप के लिए निवाचित हाती है। अगलैण्ड की काम स समा में 6351, अमेरिकी प्रतिनिधि सदन में 435, कनाडा की कॉम स समा म 265, आस्टेलिया के प्रतिनिधि सदन म 122, फच चतुथ गणराज्य की राष्टीय समा म 627, सघ सोवियत मे 791, भारतीय लोकसमा मे 520 एव स्विटजरलैण्ड की राष्ट्रीय परिषद मे 200 सदस्य होते हैं। विभिन्न देशा म प्रति सदस्य प्रतिनिधित्व की मन्या भी भिन्न मिन्न है । मताधिकार

^{1 1973} ई म काम स सभा की सदस्य-सख्या 630 थी । लेकिन 5 अतिरिक्त तवीन निर्वाचन क्षेत्रो का निमाण किया गमा है। फरवरी 1974 के निर्वाचना में 635 सदस्यों का निवाचन हुआ है।

² सन 1958 म 738 सदस्य थे।

^{3 1962} ई के सबधानिक सशाधन के अत्तगत सदस्य सख्या 200 हा गयी है। इसके पूत्र यह प्रस्था 196 थी।

एव उनभ सम्बिधित वार्ते मो हर देश म भिन्न हैं। अनेन देशा म एकसदस्यी ता अप देशा म बहुसदस्यी निर्वाचन क्षेत्र हैं। इस अध्याय म नुख प्रमुख देशा के निम्न सदमा ना अध्ययन किया गया है जिससे नि उनस सम्बिधत समस्याना की सरसता प्रयोग समोक्षा की जा सने।

ब्रिटेन का निम्न सदन-कॉम स सभा

ब्रिटिश काम स समा सदय ही एक निर्वाचित सदन रहा है। इस समय इसकी कुल सदस्य मन्या 635 है। इसक पूत्र 630 थी। इनम 511 इनलण्ड, 36 वेल्स, 71 स्काटलण्ड एव 13 उत्तरी आयरलण्ड का प्रतिनिधित्व करते थे । कॉम स समा की इस मदी व प्रारम्भ म सदस्य सख्या 707 थी, 1945 इ.म. 640 एव 1955 ई. में 620 सदस्य थे। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1948 (The Representation of the People Act, 1948) के द्वारा सदस्य संस्था 613 प्रान बहुत अधिक और न बहुत कम रखन का विधान किया गया था। 1954 ई म काम स सभा (स्थान पुनविमाजन) अधिनियम, 1949 को सदाधित करक इयलण्ड, वेल्स, स्काटलैण्ड एव उत्तरी आयर लैण्ड म प्रत्यक के लिए प्रथक प्रथक चार स्थायी सीमा आयोगा की स्थापना की गयी थी एव निर्वाचन क्षेत्रा का कम से कम 10 वर्षों एवं अधिक से अधिक 15 वर्षों म पुनविमाजन का विधान किया गया। 1954 ई के पुनविमाजन के अधीन 5 पुराने स्थाना को समान्त किया गया तथा 11 नवीन निर्वाचन क्षेत्रा की स्यापना की गयी। सभी सदस्य एकल सदस्यी निर्वाचन क्षेत्री से चुने जात हैं। 1944 ई के कामन्स समा (स्थान पुनगठन) अधिनियम एव 1948 ई के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के पूर्व कुछ निर्वाचन क्षेत्र दो सदस्यों भी थे। विश्वविद्यालय के स्नातनी एवं व्यापारिक सस्यानी का भी अतिरिक्त मतदान के अधिकार थे। लेकिन अब बहल मतदान व्यवस्था पूजत समाप्त कर दी गयी है। 'एक व्यक्ति एक मत (one man one vote) का नियम पूजत स्थापित हो चका है। काम संसभा का रूप अब पूजत प्रजाता त्रिक है। काम स सभा का लोकत जीकरण

काम स समा सदव ही लोकता त्रिक सदव नही था। उसका लोकत त्रीकरण 1832 ई से प्रारम्भ हुआ है। इसके पूज बहुत कम व्यक्तिया को मताधिकार प्राप्त था एव सम्पत्ति सम्बन्धी याय्यताएँ थी। इनलण्ड तथा बेल्स के सम्पूण ग्रामीण क्षेत्र में के बच 2 ने लाख मददाता थ। वे 80 जिल्लिंग वापिक लगान वाली भूमि के स्वामी थे। मताधिकार केवल पुरुषों को प्राप्त था। नगरों मं मताधिकार को कोई व्यवस्था नहीं थी। सम्भूण देश म तथाकथित स्वत त जन (freemen) सम्बन्धी एक सी मतदान व्यवस्था नहीं थी। कुछ नगरों मं मताधिकार जैंगियों पर गिनने योग्य था, ता नहीं सभी वयस्त्र पूरुष पतदाता थे।

इसके अतिरिक्त विसी निहिष्त नियम के अनुसार निवाबन क्षेत्रों का निर्माण नहीं होता था। एक पुराने नियम के अनुसार प्रत्येव शहरी एव प्रामीण क्षेत्र, वरी (Borough) एवं काउंटी (County) को दो प्रतिनिधि चनन का अधिकार था, चाहें उनकी जनसध्या कुछ भी क्या न हो। फलत एक तरफ तो लाखा की जनसध्या वाले नगरा द्वारा केवल दो सदस्य भेजे जाते थे ता कुछ ऐसे कस्वे भी थे जो उजड चुके थे पर तु वे भी दो प्रतिनिधि भेजने ने अधिकारी थे। औद्योगिक शांति के कारण वहुत से देहाती क्षेत्र उजड चुके थे और वर्रामध्म, निवरपुल जैस छोटे छोटे गांव अव वर्ड शहर वन गये थे। पर तु प्रतिनिधित्व की वही पुरानी वर्तविधी। फलस्वस्थ अनेक हास्यस्यद विषमतार्थ उत्पत्र हो गयी थी। ओल्डसेरम (Old Sarum) नामक शहर मे केवल दो ही निवासी रह गये थे जो रहते भी कही व यत्र थे। इन दो व्यक्तियों को भी दो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्रान्त था। अध्वरटन (Underton) नामक वरो समुद्र म विलोन हो गया था, पर तु उसके नाम पर भी दो प्रतिनिधि भेजे जाते थे। ऐसे निर्वाचन क्षेत्र सहै गले निर्वाचन कोत्र (Rotten Boroughs) वहे जाते थे। इसके अतिरिक्त अप वरों मे प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त थे। यह निर्वाचन क्षेत्र स्ववहार मे भूस्वाधियों की वेव मे अवित अधिकार मे होते थे। यह निर्वाचन क्षेत्र स्ववहार मे भूस्वाधियों की वेव मे अवित अधिकार मे होते थे और इहे जेवी निरावन क्षेत्र (Pocket Boroughs) की सजा वी जाती थी। ऐसे निर्वाचन कीनो का जुलेकाम सोदा होता था और जो जमीदारों को अधिक पूर्य चुलाता था बही इन वरा से निर्वाचन हो जाता था।

1830 ई म उदार दल विजयो हुआ था। 1832 ई म कॉन ससमा ने सुभार विषेयक पारित किया एव मताधिकार तथा निवासन क्षेत्रों का पुर्तिकालन किया गया। 1832 ई के सुवार वियेयक के अतगत प्रामीण एव सहरी क्षेत्रों के लिए समान व्य- स्था रखी गयी अर्थात 40 शिलिंग बार्यिक क्षान या किराये वाली अर्थात 40 शिलिंग बार्यिक क्षान या किराये वाली अर्थल सम्मत्ति के स्वामी या किरायेदार को मताधिकार प्रदान किया गया। फतस्वरूप मतदाताओं दो सच्या में 2 र्रेड लाख की बिंह हुई। निष्प्रमावी एव जेवी वरो (Pocket Boroughs) को समाप्त कर दिया गया। 56 वरा को मताधिकार स विचत कर दिया गया एव 30 वरो में एक एक सदस्य कम किया गया। 22 वहे नगरों को दो सदस्य एव 20 अन्य नगरों को एक सदस्य निर्वाचित करन का अधिकार दिया गया। कुल निवासन 150 स्थानों का पुर्वावभागन किया गया। इसते घने आवाद क्षेत्रों को अधिक प्रति निधिस्य प्राप्त हुआ। वास्तव में इस विषयक हारा उच्च मध्यम यग को मताधिकार प्रदान किया गया । वास्तव में इस विषयक हारा उच्च मध्यम यग को मताधिकार प्रदान किया गया था। वोकिन सववाधारण को मताधिकार प्राप्त नहीं हुआ और पूण रूपेण प्रचात न की स्थापना भी नहीं हुई। इस विषयक ने मविष्य के लिए तिस्स देह माग प्रवस्त कर दिया था।

1832 ई का सुषार अधिनियम अस तोपजनक था। जनता सीघ्र ही वयस्क मताधिकार की माग करने लगी। चाटिस्ट आ दोलनकारिया ने निम्न 5 मौंगे प्रस्तुत की थी (1) वयस्क पूरुप मताधिकार, (2) समान आकार के निवाचन क्षेत्र, (3)

⁴ Adams G B Constitutional History of England 1956, p 435

⁵ Adams G B op cst p 447 and Ogg and Zink Modern Foreign Governments, 1956 p 191

गुप्त मतदान, (4) चापिक ससदीय निर्वाचम, (5) सम्पत्ति सम्ब धी योग्यता का अत, एव (6) ससद सदस्यो को बेतन दिया जाय।

1867 ई के हितीय सुधार अधिनियम के द्वारा नगरों के सभी श्रमजीविया को मताधिकार प्रदान किया गया। फलस्वरूप मतदाताओं की सस्या म 10 लाख की वृद्धि हुई। 1872 ई के मतदान विधेयक (Ballot Act) के द्वारा गुन्त मतदान की व्यवस्था प्रारम्भ हुई।

1884 ई के लोकत्रिय प्रतिनिधित्व विधि के द्वारा यामीण क्षेत्रों म श्रीमकों को मी मताधिकार प्रदान किया गया। इसमें मतदाताओं की सल्या म 20 लाख की विद्ध हुई एव पूण वयस्क मताधिकार की स्थापना हो गयी। के 1885 ई के ससदीप कानून द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों का पुनविभाजन भी किया गया। इस समय तक दिन्धाकों मताधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। 'एक व्यक्ति एक मत का सिद्धात भी स्थापित नहीं हुआ था। 'विक् व्यक्ति एक मत का सिद्धात भी स्थापित नहीं हुआ था। विवाचन क्षेत्र भी असमान थे। कुछ लोग कई स्थानों की योगदात के कारण एक से अधिक मत देते थे। अधिकाश निर्वाचन क्षेत्र भौगोलिक थे। परातु कुछ निर्वाचन स्थापक आधार पर भी गठित थे।

1918 ई के लोक प्रतिनिधित्व अविनियम द्वारा इन दोपो को दूर करने का प्रयास किया गया। वहुल मतदान पर प्रतिव व लगा दिया गया एव मताधिकार म वृद्धि की गयी। सम्भित्त सम्बन्धी मताधिकार को योग्यता को समाप्त कर दिया गया एव वयस्क पुरुष मताधिकार रूथापित किया गया। 21 वय वयस्क तो आपु सीमा निश्चित्त की गयी। 30 वय या उससे अधिक आयु की हिन्यो को मी मताधिकार प्रतान किया गया। हिन्यो के मताधिकार के सम्बन्ध मं यह व्यवस्था थी कि उई या उनके पतियो को स्थानीय सस्याथा का मतदाता होना चाहिए। 1928 ई के लोक-प्रतिनिधित्व अधिनयम द्वारा हिन्या के मताधिकार सम्बन्धी इन प्रतिव धो को हटा दिया गया। एव उह पुरुषो के समान ही मताधिकार प्रवान किया गया। 1948 ई ने जन प्रतिनिधित्व अधिनयम द्वारा सम्बन्धि नवांचनो म बहुल मतदान को समाप्त कर दिया गया। 1970 ई म 18 वप की आयु के प्रत्यक स्त्री पुष्प को मताधिकार प्रवान किया गया। है।

कॉम'स सभा का कायकाल

कॉम समा का कायबाल 1911 ई के संसदीय अधिनियम द्वारा 5 वर्ष निरिचत कर दिया गया है। इसके पूज सप्तवर्णीय अधिनियम 1715 ई (The Sep-

⁶ Ibid, p 448

⁷ Ibid p 460

⁸ इस विधेयक की व्यवस्थाला एव निर्वाचन-पद्धति सम्ब धी अय बाता ना 1949 ई कजनश्रतिनिधित्व अधिनियम म समिचित क्यि। गया है।

⁹ Adams, G B op sit , pp 463 64

¹⁰ Ibid , pp 465 66

tennial Act, 1715) के अधीन इसकी अवधि 7वप थी। ससद कॉम स समा की जनधि का विधि द्वारा घटा या वढा सकती है। प्रधानम त्री के परामश पर राजा की कॉम स समा को विषटित करने का अधिकार है। तत्सम्ब घो परम्परा सुनिश्चित रूप मे स्थापित हो चकी है। 1906 ई से 1950 ई तक की अवधि म नाम स समा का नायकाल पूरे 5 वप एक बार भी नहीं रहा है, उससे कम या अधिक ही रहे हैं। दौना विश्य-युदो के काल म उसका कायकाल 5 वप स अधिक रहा था। वॉम स सभा के काय-काल म बद्धि या ह्यास से सम्बाधित प्रस्तावों का लाउसमा द्वारा समधन किया जाना आवश्यक होता है। दिसम्बर 1910 ई में निर्वाचित ससद का 1918 ई में विघटन हुआ था। ससद न अपन कायकाल में इस अवधि के बीच में पाँच बार वृद्धि की एव प्रथम विश्वयद की समाप्ति के बाद ही नये निवाचन हो सके थे । इसी प्रकार, नवम्बर 1935 इ मे निर्वाचित ब्रिटिश ससद 9 वप 6 माह के उपरा त 1945 ई म विघरित हुई थी। 1910 ई एव 1911 ई म तीन प्रार निर्वाचन (10 जनवरी, 1910, 19 नवम्बर, 1910 ई एव 31 जनवरी, 1911) हुए थे। 1919 ई मे निर्वाचित ससद 3 वय 8 माह के बाद 1922 ई मे विघटित हो गयी। 1924 ई म दो बार (जनवरी एव दिसम्बर) निवाचन हुए थे। 1929 ई, 1931 ई एव 1935 ई म रमश निर्वाचन हए। 1949 ई एवं 1950 ई के वर्षी म काम स समा के एक वप के पश्चात ही निवाचन हुए थे। विगत 150 वर्षों म केवल तीन बार 1867-73 ई, 1951 55 ई एव 1955 1959 ई तक ब्रिटिश ससद ने अपनी पण अवधि तक काय किया है।

काम'स समा की सबस्यता सम्ब थी योग्यताए11

सभी वयस्क स्त्री पुरुषा को जो बिटिश प्रचाचन ह, यतदान का अधिकर प्राप्त है। वे किसी भी उपनिवेश ने निवासी हो सकत है। वयस्कता की आयु सीमा 21 वप धी। जब 18 वप है। इससे कम आयु ने व्यक्तियों को मतदान का अधिकार नहीं है। विदेशी, अस्प्रयस्क, पादरी, 12 विश्वप्त, पीयर अर्थात लॉडसचा के सदस्य, देशब्रीही एव महापासक के अपराधी जि होने नारायास की अविध पूज नहीं की है या अविध के पूज सामा प्राप्त नहीं कर सके हैं तथा सबदीय निवाचना म अरूट एव अनुचित तरीको के अयोग क दोषी व्यक्तियों का मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसे क्यतिया का सामा भारत नहीं है। ऐसे क्यतिया का सामा मी सदस्यता के लिए प्रत्याची भी नहीं हो सनते। काम सामा अयोग्यता अधिनिमम 1957 ई (House of Commons Disqualification Act, 1957) के अधीन उच्च पायालय के यावाधीं से लेकर दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) तक अनेक

¹¹ Refer to House of Commons Disqualification Act 1957, Quoted the United Kingdom Constitution, B I S Pamphelet No P F P 4758/68, pp 17 18

¹² इगलैण्ड, आयरलैण्ड एव स्काटलण्ड के चर्चों के पार्टीयो एव रामन कथोलिक चर्च के पार्टीया को मताधिकार प्राप्त नहीं है।

यायिक अधिकारिया, ज्ञाउन के लोक कमचारिया (Cavil Servants), तेता, विदेश एव उपितिया सेवा तथा पुलिस कर्मचारी कॉम स ममा के सदस्य नहीं हो सकत । राष्ट्रमण्डल (Commonwealth) के बाहर के किसी देश की व्यवस्थापिका एव किसी आयोग, बोड या यायाधिकरण का सदस्य भी कॉम स समा का सदस्य नहीं हो सकता ।

प्राचीन परप्परा के अनुसार कॉम स समा की सदस्यता अधिकार न होकर कतव्य माना जाता है। आज मी कॉम स समा का कोई सदस्य औपचारिक रूप से त्यापपन नहीं द सकता। परत्यान के इच्छुक सदस्यों की अप्रत्यक्ष रूप से ही परत्यान करता पड़ता है। काउन के अधीन किसी साम के पद को स्वीकार कर तेने पर काम त समा का सदस्य स्वत हो जाता है। अधी सदी से ही जाउन के अधीन मन्त्रियन्द को छोड़कर लाम के किसी अय पद को ग्रहण करना कान माना की सदस्याता के लिए अयोग्यता (disqualification) माना गया है। बैतिक आफ दी हण्डेड ((Baibtí of the Hundred) एवं मेनर ऑफ दी नाम हैंड (Manor of the North Head) नामक दो पद ऐसे ही है प्य वे बीघकाल स समान्य हो चुके हैं। कॉम स सभा का जो सदस्य उसकी मदस्यता से मुक्त होना चाहते हैं वह उनन स किसी पद पर निमुक्ति की प्रायना करता है। प्राय इस प्रायना को अस्वीकार नहीं किया जाता है। यह रोना पद बित्त मनी (Chancellor of the Exchequet) के अधिकार क्षेत्र म है और लाम के अवतिनक पद माने वांते हैं।

काम स समा द्वारा निम्नलिखित तीन महत्वपूण काय सम्पादित किये जात है

- (1) विधि निमाण,
- (2) प्रधासन पर नियायण एव निरीक्षण, एव
- (3) राष्ट्रीय वित्त पर नियात्रण।
- (1) विषाधी शिवतर्थं कॉयन्स समा की 1911 ई के ससदीय अधिनियम के अन्तात विवि निमाण सम्बंधी व्यापक श्रास्त्रियाँ प्राप्त हो गयी हैं। 1949 ई के ससदीय अधिनियम के द्वारा लाइसमा की विलायकरारी श्रास्त्र को कम करके एक व्यापक सीमित कर दिया गया है। सभी वित्त विवेचक काम स समा म ही प्रस्तुत विदे लाइसमा को प्राप्त इस क्षेत्र य नाई श्रास्त्र तही है। यह अधिक स अधिक रियो आह तही है। यह अधिक स अधिक रियो प्राप्त नही है। यह अधिक स अधिक रियो प्राप्त नही है। यह अधिक स्थापत राजा अध्यापत कर सकती है, उसने स्थापत कर तमा या अध्यापत विश्व कर एक माह म विवार व्यक्त कर सकती है, उसने स्थापत कर तमा म सव्यक्त कर सकती है। विवार प्रदूर्ण पर मिनोय विवाय का महत्त्र का सवत्र प्रस्तुत कि स्थापत स्यापत स्थापत स्य

एक वप का अत्तर होता है, तो विषेयक लॉडसमा का विरोध होते दूए भी पारित हो जाता है । सक्षेप में, कॉम स समा को वित्तीय एवं गर-वित्तीय दोनों ही प्रकार के विषेयकों में पारित करने के अतिम अधिकार प्राप्त हैं।

(2) कायपालिका एव प्रशासन के नियन्त्रण एव निरीक्षण सम्ब धी शक्ति-ससद कायपालक अधिकारी नही है। लेकिन क्राउन एव कायपालिका के कार्यों एव ससदीय विधियों के प्रशासन पर वह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रीति से कठोर निय नण रखती है। कॉम स सभा के प्रति मित्रमण्डल अपने कार्यों एव नीतियों के लिए उत्तरदायी होता है। अभिसमय के अनुसार काउन द्वारा बहुमतदल के नता को प्रधानम श्री नियुक्त किया जाता है। मित्रमण्डल के मुख्य सदस्य कॉम स समा के ही सदस्य होते है। अभि-समय के अनुसार प्रधानमात्री भी कॉमास सभा का ही होना चाहिए। कामास सभा का विश्वास लोने पर मित्रमण्डल को त्यागपत्र देना पडता है। इसके अतिरिक्त सदस्यो को प्रश्न पूछ कर शासन य सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। वे वाद विवाद की माग करके शासन की नीति की आलोचना कर सकते है। किसी नीति सम्बाधी प्रकत की समीक्षा वजट काल में उस विभाग की मागो पर विचार के समय की जा सकती है। सम्पूण मिन्यण्डल के विरुद्ध अविश्वास (No Confidence) एव निदा प्रस्ताव (Censure Motion), स्थवन (Adjournment) एव ध्यानाकपण प्रस्तावा (Call Attention Motions) को उपस्थित करके शासन को नियन्तित निया जाता है। अविश्वास एव निदा प्रस्ताव तथा विभाग की माँगा म कटौती के प्रस्ताव के पारित होने का अब मित्रमण्डल का पतन होता है।

संसद-सदस्यों के प्रस्त पूछते का अधिकार बह महत्यपूष उपकरण है जिसक द्वारा व धासन के काय की आलीचना कर सकते हैं तथा उसका ध्यान जनता की कठि-नाइयों को ओर आकंपित कर सकत है। प्रश्न पूछना शासन के कायों पर सबसेंग्रंट अवरोध है। शासन का प्रत्येक विभाग यह जुम्मय करता है कि उस पर निर तर इटिट रायों जा रही है। फलस्वरूप में सज्या रहते हैं। यदि किसी प्रश्न के उत्तर म सदस्या को सतीय नहीं होता तो वे सदन के काय वो स्थानित करके सावजनिक महत्व मं किसी प्रस्त पर विचार करने का प्रस्ताव कर सकते हैं। विदोय कठिनाई, आलोगना एवं किसी प्रस्ताव को उवस्थित करने के तिए सदस्यगण ध्यानाक्यण नोटिस ये सार्थ है। शासन की किसी महत्वपूण नीति पर विचार करने या शासन के प्रस्तु निया पा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए विरोधों दन के नेता को तिथि निश्चित करा मी गोग करने का अधिकार होता है।

सासको के अनुसार 'प्रस्त पूछन की पद्धति के महत्वपूष परिणाम हुए हैं। इसस राज्य के विभिन्न विभागों के काय जनता की निगाह म जा जात है। 'यर्द नीवरदाह की जादता स उत्वन्न खतरों को पूरी तरह समास्त तो गहा पिन उत्तर अ व्यवस्थ कर तेती है। लास्की मी इंप्टिंग प्रप्रत पूछकर सासन मो जाता थी।' प्रदेश में प्रदेश कर की दूर करने केटर को दूर करने केटर को दूर करने की मुचना दी जाती है। वर्गम मा सभा "

•

जन-कृष्टा को अभिव्यक्त करना (ventilation of guevances) है। जन करने की अभिव्यक्ति से अथ जनता के कच्टा पर ध्यानाकपण की शक्ति स है। जहाँ इस शक्ति का अमाव है वहा अत्याचार का होना अनिवाय है ।12

लास्की के अनुवार काम व समा का मुख्य काय शासन का निर्माण करना है जो उसके विश्वासपय त विधि निर्माण सम्बन्धी निर्देश हे सके। विधि निर्माण की निर्देश शक्ति शासन के हाथ में दकर कॉम स समा को शासन के कायरम पर विचार करने की सक्ति एवं अधिकार स्वतं प्राप्त हो जाता है। जासन निर्माण क परचात विधि निर्माण के अतिरिक्त, लास्की के अनुसार, कॉम स सभा के अय काय निम्नलिखित हैं — जनता के कप्टा का निवारण करना, सुचना प्राप्त करना एव बाद विवाद के माध्यम से सावजनिक विषयो म जनता की रुचि जागत करके उस जन जीवन म विक्षित करना है। इसके अतिरिक्त सदन का एक काय अपने मे से योग्य सदस्यों का चुनाव करना है। सदन के इस चुनाव काय से अय जस चहुर मनोवज्ञानिक पढ़ित से हैं जिसके फलस्वरूप एक सदस्य को तो रयाति प्राप्त होती है और दूसरा अंतफल हो

काम स समा वाद विवाद (debate) की हिन्दि में राष्ट्र का चर्चा स्पल है। विश्व निर्माण काल में एवं शासन की समीक्षा के वीरान सदन में बाद विवाद होता है। कमी-कमी सदस्यों के द्वारा धासन की किसी नीति या किसी सावजनिक महस्व के प्रस पर भी बाद विवाद की माग की जाती है। काम स समा म यद्यपि वाद विवाद का स्तर निरतर गिर रहा है परतु इसके महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

(3) राष्ट्रीय बिल पर निय त्रण-नाम स समा राष्ट्र की वित्तीय ध्वक्त्या-जाय एवं व्यय—को स्वीकृति दन के अधिकार से उस पर नियानण रखती है। धन की 13

The power to ventilate grievances means the power to compel attention to grievance ment so sure is always wide Laski Nothing makes responsible Govern where this power is absent the room for tyranny 1952, p 149 Parhamentary Government in England

The business of House of Commons is 'primarily to make a confidence it is prepared to make a state of the Covernment its prepared to make a state of the Covernment its prepared to make a state of the Covernment its prepared to make a state of the Covernment its prepared to make a state of the Covernment its prepared to make a state of the Covernment its prepared to make a state of the Covernment its prepared to make a state of the Covernment is prepared to the Covernment is p Confidence it is prepared to entrust that initiative? (p. 143) By leaving the initiative in legislation to the Government the House assures trail of the legislation to the Government the House assures itself of the Capacity to consider a programme's (6) 144) The Capacity to consider a programme's capacity to capacity Avous assures used of the capacity to consider a programme the functions the House must perform? There is the ventilation.

There is the ventilation. of greener in the extraction of information the business debate to sustain public inferest and to educate in the stemple inferest and to educate the stemple in the stemple There is the extraction of information

There is the ventuation

There is the extraction of information

There is the extraction of information

There is the extraction of information. it is the significance of what is being done. There is the selecin it the significance of what is being done. There is the series the function of the Houses-by which is meant that subtle and another fails to make one member makes a reputation and another fails to make one -Lasks op at , p 144

स्वीकृति को लेकर ही 17वीं सदी में इगलैंग्ड में राजा एवं ससद में संघप हुआ था और चाल्स प्रथम को प्राणो से हाथ घोना पडा तथा जेम्स द्वितीय को सिहासन त्यागना पढा था। 1688 ई में यह निविवाद रूप में निश्चित हो गया था कि ससद ही राष्ट्र के वित्त की सरक्षिका है। कॉम स सभा म ही वित्त-विधेयक संवप्रथम प्रस्तुत किये जात है। कॉम स सभा की स्वीकृति के विना न कोई कर लगाया जा सकता है, न कोई धन-राशि व्यय की जा सकती है। 15 कॉम स समा काउन द्वारा धन की माग करने एव कर प्रस्तावित करने पर ही व्यय एव कर लगाने की स्थीकृति दे सकती है। इसका जय यह है कि विलीय मामला में सरकार को पहल करने की शक्ति है। इस्कींन के शब्दा म "काउन द्वारा धन की माग की जाती है, कॉम स उसे स्वीकृत करते हैं, लॉड स उस पर अपनी स्वीकृति देते हैं, लेकिन कॉम स उस समय तक धन को स्वीकृत नहीं करते जब तक कि नाउन द्वारा उसकी माय नहीं की जाती।16 काम स समा नाउन द्वारा प्रस्तावित करा या व्यय की राशियों में कटौती कर संकती है लेकिन वृद्धि नहीं कर सकती। दिसम्बर 1706 ई को कॉम स ने एक प्रस्तान द्वारा यह स्वीकार किया कि यह सदन सावजनिक सेवा के लिए धन हेत काई आवेदन काउन की सस्तुति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यही 11 जुन, 1713 से स्थापी नियम बन गया है।17 लाइसमा को वित्तीय मामला मे कोई शक्ति प्राप्त नहीं है।

काम स द्वारा वजट पारित होने पर हर देनदारी को नियानक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General) द्वारा अविकृत किया जाता है। वार्षिक लेखा की जाच सावजनिक लेखा समिति (Public Account Committee) द्वारा की जाती है। समिति द्वारा प्रतिवेदनो को काम स समा के समक्ष रसा जाता है।

प्रश्न पूछकर एव बाद-विवाद क समय वित्तीय गीति की आलोचना करके भी राष्ट्रीय वित्त पर निय नण रखा जाता है। नाम स समा करों से प्राप्त राजस्व पर वित्त विधेयक (Inance Act) एव उपाय एव साधन समिति (Ways and Means Committee) म होने वाले विवाद के माध्यम से निय त्रण रखती है। राष्ट्रीय धन के व्यय पर ससद पूर्ति समिति (Committee of Supply) य होने वाले विवाद एव विगियोग विधेयक (Appropriation Act) को स्वीकृत करके तथा ससद के प्रति उत्तरदायी नियानक एव महालेखा परीक्षक के अधिपरण (authorisation) के माध्यम

¹⁵ Sir Thomas Erskine May Treatise on the Law, Privileges, Proceedings and Usages of Parliament, 1964, p 40

^{16 &#}x27;The crown demands money the Commons grant it, and the Lords assent to the grant but the Commons do not vote money unless it is required by the Crown "—Erskine op at, 13th edn, p 493

¹⁷ Resolved, that this House will receive no petitions for any sum of money relating to public service but what is recommended from Crown (i.e. by a munister). Commons Journals vol XV p 211 11th December 1706 cited the United Kingdom Constitution II I S., op ct., p 20

स नियंत्रम् रसती हैं। सस्तीय सावजनिक नेया समिति द्वारा तसा ना परीशण किया जाता है।

संबंद म, कॉम स समा विभिन्न तरीको सं कायपालिका पर निय त्रण रसती है, जिसे कि साित काल म ससद की स्वीकृति के विना सेना को रसने का कीई मार जनता वहत नहीं करेबी, कॉम स तमा हास अनुदान की मांग प्रति वप त्वीकृत की जानी चाहिए अनुरानित धन राजि को स्वीकृत यह य ही व्यय किया जाना चाहिए, एव मित्रमण्डल अपने कार्यों के लिए काम स समा के प्रति उत्तरदायी होता है। कॉम स सभा की स्थिति की समीक्षा

आलोचका ने काम स समा को वार्ता की दुकान (talking shop) की समा दी है। कार्ताइल ने कीय म यह कहा या कि विस्त ने शायद ही ऐसा कभी देखा वा हा कालाइल न काव न वह कहा था क करव न चायव हा एटा क्या पता ही कि 600 मने महान साम्राज्य के विधि निर्माण एव प्रसासन काय में इस प्रकार सतान हैं। कालंडल का यह व्यय भ्रामक है। पर तु यह अस्वीकार नहीं किया जा तकता कि काम स समा म कुछ कमियाँ हैं।

रमने म्योर में अनुसार संसद का काय वालोचना करना एवं राष्ट्र की तरफ तं नियात्रण करना है। उसका काय प्रधासन की जांच करना भी है। यह देखना नी उसका काय है कि प्रचासन मितव्ययता एवं सक्षमतापूर्वक चेनाया जाता है। शासन हारा मस्ताबित हर नयी विधि एवं अध्यादेश की संजयता से परीक्षा करना एवं जसे सहोोधित करना उसका काय है। प्रस्तावित करों के सुनिस्चित होने के सम्बन्ध म समस को सनुष्ट होना चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि जनता पर कर का कम से कम मार पड़े 118 महत्र यह उठता है कि आलोचना एवं नियं नण के इन कार्या को कामस तमा क्या ठीक प्रकार स सम्पादित करती है? क्या उसका वतमान सवडन एव जरूर राष्ट्र की इच्छा एव विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखता है ? क्या काम स समा राष्ट्र का पूज प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है ?

काम स समा की वतमान निर्वाचन प्रणासी आसोचको की हृष्टि म दीवपूर्ण है। प्रचलित बहुमत मतदान व्यवस्था के कारण कामन्त समा जनमत को मती प्रकार अभिव्यक्त नहीं करता। निर्वाचन क्षेत्रों म दो या अधिक प्रत्याशियों के माय समय हीने की दला म यह सम्मन है कि विकयी दल के उम्मीदनारा को कुल मतदातामा ना त्याद बहुमत म्राप्त न होने पर भी वे बहुमत म निवयो घोजित किये जासे। इतियह के सामा व निर्वाचनो के उपलब्ध बाकडा से उक्त कथन की पुष्टि होती है। सन 1918 ई के सामाय निर्वाचन में संयुक्त दल (coalition) को काम स समा म 472 स्थान एव बच बतो को 130 स्वान प्राप्त हुए थे। सबुक्त दल एव बच दलो को प्राप्त स्यातो का अनुवात 4 और 1 या जबकि संयुक्त दत्त को 52% तया अय दत्तों की

¹⁸ Halsbury Laws of England Vol 28 3rd (Sumonds) edn, (1929) 19 Ramsay Muir How Britain is Governed (1951) p 117

48% मत प्राप्त हुए थे। यदि दोनो दला को प्राप्त मता के अनुपात म स्थान प्राप्त हुए होत तो 342 ने स्थान पर समुक्त दल का नेवल 30 का बहुमत होता। रैमवे म्योर के अनुसार यह राष्ट्रीय विचारो की गम्मीर विकृति है। इसस शासन ने हाय मजबूत हुए और उसे अमर्यादित अधिनायण त्व प्राप्त हो गया। 10 समुक्त दल के पतन के परचात 1922, 1923 एव 1924 ई मे निवचित्त हुए थे। 1922 ई मे अनुदार दल को 347 स्थान एव 79 का स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुया था लेकिन अनुदारल को कुल मतो के केवल 38 प्रतिवात मत प्राप्त हुए थे। उदारवादिया को 28 5 प्रतिवात एव थम दल को 29 5 प्रतिवात मत प्राप्त हुए थे। उदारवादिया को 28 5 अनुदार तथ वस्त को 29 5 प्रतिवात मत प्राप्त हुए थे। स्पष्ट है कि प्राप्त मता के अनुपात म अनुदार दल नो स्पष्ट बहुमत नहीं मिलना चाहिए था और उदारवादियों को प्राप्त मता के अनुपात म कम स्थान मिले थे।

1923 ई के निर्वाचना मं अनुदार दल को 38 प्रतिचत मत मिले थे लेकिन 1922 ई की तुलना म 90 स्थान कम मिले थे। इस बार स्पष्ट बहुमत के स्थान पर 100 सदस्यों से वे अस्थमत म थे। फिर भी उन्ह प्राप्त सता के अनुपात से 24 स्थान अधिक मिले थे। 1924 ई के सामाय निर्वाचना म जदार दल को प्राप्त मता के अनुपात में अनुपात में प्राप्त मता के अनुपात में प्राप्त मता के अनुपात मं 108 स्थान मिलने चाहिए थे जबकि उन्हें केवल 42 स्थान ही प्राप्त हुए थे। अनुदार दल को नेवल 47 प्रतिस्त मत मिले थे लेकिन 415 स्थान प्राप्त हुए थे जबकि प्राप्त मता के अनुपात में उन्हें केवल 289 स्थान मिलने चाहिए थे। इस प्रश्रा लुदार दल 5 वथ तक निरदुश दन से सासन करता रहा। 1929 ई के निर्वाचनों म अम दल को 36 प्रतिस्त मत मिले लेकिन उन्हें 224 के स्थान पर 288 स्थान प्राप्त हुए थे।

1935 ई के निर्वाचनो म सासन को 428 स्थान एव विरोधी दल को 184 स्थान मिले पेजविक विरोधी दल को शासकीय दल को प्राप्त मतो के 80% मत प्राप्त हुए थे। 1945 ई के निर्वाचना म अनुदार दल को श्रम दल की तुलना मे आधे स भी कम स्थान मिले थे अविक सब स्वे को प्राप्त मतो के 2/3 मत से अधिक मत अनुदार दल को प्राप्त हुए थे। 1959 ई म अनुदार दल को 49 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे परन्तु 58 प्रतिशत स्थान काम समा से प्राप्त हुए। अत वॉम स समा जनमत का विकृत रूप ही प्रस्तुत करती है।

अर्पस्थक दलो की स्थिति इस निर्वाचन पद्धति के अंतगत और भी दयनीय होती है। या तो ऐसे दल राजनीतिक रगमच से पूरी तरह हट जाते हैं या उनको उचित प्रतिनिधित्य प्राप्त नहीं होता। ब्रिटेन भे उदार दल की यही स्थिति है। जानिमंद्र को प्राप्त कर करता है कि तीन के प्रत्य कर कर के स्वाचन प्राप्त न हो स्थोकि अनुदार या श्रम दल के किसी न किसी प्रत्याची को उससे अधिक मत प्राप्त हुए होसे। 2º 1955 ई म उदार

²⁰ Ibid, p 123

²¹ Jennings, Sir Ivor The British Constitution, (4th edition), p

दल को 7,22 402 मत प्राप्त हुए वे पर तु उस क्वल 6 स्थान प्राप्त हुए थे। 1959 ई म जह 16,40,761 मत प्राप्त हुए कि जु उनक सदस्या की सम्या 6 ही बनी रही। स्मरणीय है कि इस निर्वाचन म जहाँ एक अनुवारक्तीय सदस्य 38,000 मतराताना का प्रतिनिधित्व करता था वहाँ उदार दल या एक सन्स्य 27 500 मता वर प्रति निधित्व करता था।

उपरोक्त अक्टिंग सं यह स्पष्ट है कि कामना की प्रचलित निर्वाचन-पद्धति दोए-पूण है। अनुमानत कुल मतदाताओं वे 70 प्रतिसत मतदाता देस के राजनीतिक पटना-त्रम को जपने मता स प्रमाबित करन म असफन रहत हैं या वे ऐसी नीति या विचारधारा का समयन करने ने लिए अध्य हो जात हैं निससे कि वे सहमत नहीं होते । निविरोध निर्वाचना वे वारण अनेक मतदाताओं को मतदान का अवसर ही नहीं मिलता एवं असकल उम्मीदवारों च मता का कोई मूल्य नहीं होता।

रमने म्योर का कथन है कि हमारी निवासन पढ़ित के अधीन निवासन के जुआ वन जाने व धारण निश्चयपूर्वक कुछ नहीं वहां जा सकता । निर्वाचन क्षत्रा एव राष्ट्रीय स्तर पर इसका दूषित प्रमान पडता है। जनमत क अनुरूप दल की नीति को परिवर्तित करने के स्थान पर निवाचना म प्राप्त सफलना के आधार पर ऐसी योजनाम को अधिनामकवादी ढम से क्यियाचित किया जाता है जिह राष्ट्र नही चाहता। "राष्ट्र का इष्टिकोण इस प्रकार कं निर्वाचना से अभिव्यक्त नहीं होता वास्तविक प्रमुख राष्ट्र कं गम्भीर एव विचारवान व्यक्ति के हाथों से न रहक अविवेकी, अस्पिर व्यक्तियों के हायों में रहता है जो भय, प्रदेशना, आस्वासना में आका अपना मत देत है। यक्ति के जुजा म सफलता के हेतु इस जनसमूह को राजनीतिक जीतने का प्रयास करते हैं। यही नहीं निर्वाचन क्षेत्रा में प्रत्यासीयण थीड ने मतो की प्राप्त करने के लिए अपने छिडा ता तक की तिनावलि दे देन हैं। इसके अविरिक्त, वतमान निर्वाचन एडति के कारण योग्य एव चरित्रवान व्यक्ति ससद व लिए नहीं चूने जाते।" हमारी निर्वाचन प्रणाली म रेमजे स्वीर के सब्दों म, 'योग्य व्यक्तियो के निवाचन को कोइ प्रोत्साहन नहीं है। सक्षेप म कॉय स समा की निर्वाचन-पदीत भत्यधिक अवायपूर्ण, असःतीपजनक एव सतरनाक है।' ३

²² Walker K W Government in Britain and New Commonsealth 1965 p 60 23

The real mind of the nation is obscured not revealed, by elections conducted in this way, the real supremacy rests not with the sober and thinking elements in the nation but with the margin of unthinking waverers who can be swung this way or that by panies stunts and promises and it is to this margin that Politicians are tempted to address themselves in the gamble of power (p 126), in short our method of election is in the power (p 120), in snort our method of election is in the Muir op cit, (1951) p 127

निर्वाचन-पद्धति के सुधार के लिए अनेक प्रयास किये गये हैं। इगलैण्ड की समा-नुपातिक प्रतिनिधित्व परिपद ने एकल सन्नमणीय मतदान व्यवस्था का सुभाव दिया या । समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा निवाचित व्यवस्थापिका मे राष्ट्र के सभी वर्गों एवं हिला के ठीक प्रतिनिधित्व होने का उचित आश्वासन है। इसके अति रिक्त सभून मतदान प्रणाली (Cumulative Vote System) का भी सुभाव दिया गया है । इस पद्धति के अपनाने से मतदान प्रणाली के बहुत कुछ दोपा से बचा जा सकता है। एक जाय स्नाव Restrictive Vote System का है। लेकिन इन मत-दान-प्रणालिया का एक गम्भीर दोषयह है कि इनसे देश म बहुदलीय पद्धति का विकास होगा एव राजनीतिक अस्थिरता के लिए माग प्रशस्त हो जायेगा।²⁴ जत उपचार के रोग से भी गम्भीर परिणाम हागे।

कॉम स समा की निवाचन प्रणाली की मुख्य विशेषता यह है वि इसम शासन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है एव स्थायी शासन का निमाण होता है। स्थायी शासन की अपनी विशेषताएँ हातो है। सहद विदेश-नीति एव दीघकालीन आर्थिक विकास की योजनाजा का जिया वयन सम्भव होता है। लॉड पैथिक लॉरेस का मत या कि "हमारे लोकत न की पद्धति गणितीय आधार पर प्रतिनिधित्व की उपलब्धि पर आधारित नहीं है अपित एक ऐसे ससद का निमाण करती है जो हढ एव स्थामी

नीति के लिए स्थिर शासन का निर्माण करने म योग देती है।

सक्षेप म, बिटिश कॉम स समा विश्व का सबसे प्राचीन निम्न सदन है । वित्तीय मामलो म इसे अतिम शक्ति प्राप्त है। यह ब्यवहार मे ब्रिटिश ससद है। इसका कायपालिका पर नियानण होता है, यह सिद्धातत सत्य है परात, व्यवहार म स्थिति भिन है। प्राय प्रत्येक दश म कायपालिका अधिक शक्तिशाली होती जा रही है। ससदीय प्रणाली वाले देशा के सम्बाध म तो यह और भी सत्य है। कॉम स समा पर अब मिनमण्डल का नियानण होता है। मित्रमण्डल बहुमत दल म से निर्मित होने के कारण दलीय अनुशासन द्वारा काम स समा पर निय प्रण करता है। विधि निमाण म मित्रमण्डल ही कॉम स समा का नेतृत्व करता है। नीतियो का निर्माण मिनमण्डल द्वारा किया जाता है । सदन केवल उनको स्वीकृत करता है । व वजट मित्रमण्डल के द्वारा निर्मित किया जाता है, विक्त मात्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और कॉम स समा अधिकासतया उसे उसी रूप म स्वीकार कर लेती है। काम स समा अपने समय का 85 प्रतिशत माग शासकीय कार्यों म व्यय करती है। कॉम स समा की प्रमुसत्ता की घारणा केवल भ्रम है। अत ब्रिटेन म मिनमण्डल कॉम स समा का स्वामी है। 7 परतु विश्व के सर्वाधिक अनुमवी एव चेतन सदना म कॉम स समा की

²⁴ निर्वाचन प्रणाली के लिए देखिए अध्याय 31 1

Walker K W op cit 1965, p 61
 Neumann, R G European and Comparative Governments, p 67

Ramsay Muir op cit, 1951, p 174 27

लिए एक से अधिक प्रतिनिधि नहीं होगा तथा एक राज्य का कम से कम 1 प्रतिनिधि अवस्य होगा। 1964 65 ई के निर्वाचनों म $3\frac{1}{2}$ से $4\frac{1}{2}$ लाख व्यक्तिया के लिए एक प्रतिनिधि चुना गया है। प्रारम्भ म प्रतिनिधि सदन की कुल सदस्य-सख्या 65 थीं लेकिन 1910 ई म इसकी सख्या 435 पहुँच गयी एव 1929 ई के एक अधिनियम हारा कुल सदस्य स्थ्या 435 निश्चित कर दी गयी है। 30 प्रत्यक राज्य से उसकी जनसख्या के आधार पर प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं। अत चढ़े राज्यों को इस सदन म अधिक सदस्यता प्राप्त है। नेवेदा, डेलावेयर, ब्योमिंग एव परमाउण्ट नामक राज्यों के एक-एक सदस्य हैं जबिक बूयाक के 43 सदस्य प्रतिनिधि सदन म है। सदन का कायकाल 2 वप है। इसे घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता।

प्रतिनिध सदन को सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यताओं के अधीन प्रत्याधी को कम से कम 7 वप से सब्क्त राज्य अमेरिका का नागरिक होना चाहिए, उसकी आपु 25 वप से कम नहीं होनी चाहिए एवं उसे उसी राज्य का निवासी होना चाहिए खहा से वह निर्वाचन लड रहा है। अव यह प्रया मी विकसित हो गयी है कि उसे राज्य के साथ-साथ उस निर्वाचन क्षेत्र का भी निवासी होना चाहिए जहां से वह निर्वाचन तता रहा है। इस स्थानीय नियम (Locality rule) कहते हैं। इस नियम का सह दुष्परिणाम भी है कि दल के योग्य व्यक्ति उस समय तक किसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन म खड़े नहीं हो सकते जब तक कि व निवास सम्ब वी योग्यता को पूण न करते हा। राष्ट्रपति कजवेटट ने सोल क्ल्म (Sol Bloom) की मृत्यु के कारण पूथाक के रिक्त स्थान पर निर्वाचन लड़े के लिए पूपाक चित्र में एक सकान की किराये पर लेकर उसे अपना आवास-स्थल भीपत किया था। इस नियम के कारण क्षेत्रीय सकीणता की भावना का भी विकास हुआ है।

इसके अतिरिक्त समुक्त राज्य के किसी पद पर काय करन वाला कोई व्यक्ति पद पर रहत हुए कांग्रेस की सदस्यता के लिए प्रत्याशी नहीं हो सकता। इस ध्यवस्या का उद्देश शासन के काथरालिका एव व्यवस्थापिका विभागी में पूथक्करण रखना है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस कोई भी सदस्य अथने कायकाल के मध्य नागरिक सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। प्रतिनिधि सदन को प्रत्यक्ष रीति से जनता हारा निर्वाचित किया जाता है। एकल सदस्यी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं।

प्रतिनिधि सदन के सदस्या को निर्वाचित करन के लिए सामा यत अन सभी

^{30 1929} ई म निमित विधि को 1941 ई म पुन सद्योधित किया गया। 1959 ई म प्रतिनिधि सदन की सदस्य सस्या अस्यायी रूप म हवाई द्वीप एव अलास्का के अमेरिकी सच म सामित होने पर अस्यायी रूप से 437 निर्धारित कर दी थी। सिन 1961 ई म जनगणना के परिचामा के आधारा पर स्थायी रूप से इसकी सरया 435 निविचत कर दो गयी है।——Dgg and Ray Essentials of American Government, 1967 (Ind edn) p 187

³¹ Article 1, sec 2, cl 2 of U E Constitution

व्यक्तिया को मतदान का अधिकार प्राप्त है जो राज्य व्यवस्थापिका के निम्न सदन के लिए मतदान कर सकते हैं। अनेक राज्यों म मतदान व्यवस्थाएँ मित है। 3- सामा यत हर 21 वर्षीय अमेरिको नागरिक को मतदान का अधिकार है। 153

प्रतिनिधि सदन की शक्तिया

प्रतिनिधि सदन को प्राप्त विधायी शक्तिया के अधीन सभी सधीय विधेयका के लिए प्रतिनिधि सदन द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। सविधान मे उन समस्त विषया का उल्लेख है जिन पर अमेरिकी काग्रेस की विधि निर्माण का अधिकार है। निहित शक्तियों के सिद्धान्त (The Theory of Implied Powers) के अधीन विमायी शक्ति म वृद्धि हुई है । वित्त विधेयक सवप्रयम प्रतिनिधि सदन में ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं लेकिन सीनेट को उनमे जामूलचूल परिवतन करने का अधिकार प्राप्त है। गर वित्तीय विधेयक सवप्रथम किसी भी सदन मे प्रस्तुत किये जा सकत हैं परन्तु दूसरे सदन द्वारा भी जनका पारित निया जाना आवश्यक है। जदाहरण के लिए, यदि व प्रथम बार सीनेट मे प्रस्तुत किये जाते है तो सीनट द्वारा पारित होने पर प्रतिनिधि सदन द्वारा उनका पारित होना जावश्यक है।

प्रतिनिधि सदन को राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति एव अय सधीय अधिकारियो पर महामियोग लगाने का अधिकार है लेक्नि उसका परीक्षण सीनेट करती है। सबघानिक सशोधन को भी प्रतिनिधि सदन द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। यदि राष्ट्र पति के निर्वाचन में किसी प्रत्याधी को पूण बहुमत प्राप्त नहीं होता तो प्रतिनिधि सदन को सबसे अधिक मत पाने वाले तीन प्रत्याक्षिया मे से किसी एक को राष्ट्रपति घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

सीनट एव प्रतिनिधि सदन की शक्तिया समान है। प्रतिनिधि सदन का सीनेट के निजय पर निषेधाधिकार लगान का अधिकार नहीं है। विसीय, महाभियोग, नियुक्ति एव सम्यो के सम्बंध म सीनेट की प्राप्त विरोप सक्तियाँ उसे प्रतिनिधि सदन से अधिक शक्तिशाली बना देती हैं। इसके अतिरिक्त सीनट को जांच समितिया के माध्यम स जाच करन की व्यापक एवं सथकर शक्ति प्राप्त है। अतः प्रतिनिधि

सदन की स्थिति सीनेट की तलना में घटिया एवं निम्न है।

मौग्रेस के दाना सदना को अपने सदस्या को निष्कासित करन का अधिकार है परन्तु प्राय इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता है। उनके द्वारा अप नाग रिना को यदि इन व्यक्तिया के कार्य कांग्रेस के कार्य म वाधा उत्पन्न करत हैं, ती

³² अलबामा राज्य म मताधिकार पान क लिए साम्यवाद विराधी शपम लेना अनि वाय होता है। लुइसियाना म अग्रजी एवं मातमाचा पढ़ सरन बाते व्यक्ति की ही मताधिकार श्राप्त है। 19 राज्यो म मताधिकार क लिए सविधान पढ़न की याग्यता अपक्षित है।

³³ जाजिया (Georgia) राज्य म 18 वय न आय के व्यक्तिया का मताधिकार प्राप्त है।

दण्डित किया जा सकता है। शासन के विभिन्न विभागा को उनके कार्यों के सम्बाध में कांग्रेस के दोनों सदन प्रस्ताव पारित करके निर्देश दे सकत है एवं विभागा स उनके कार्यों के सम्बाध में प्रतिवेदन मंग्रि जा सकते हैं तथा स्वतात्र प्रशासकीय अभि-करणा की स्थापना मों की जाती हैं।

ब्रिटिश कॉम स सभा एव अमेरिकी प्रतिनिधि सदन की तुलना

कॉम स समा एव प्रतिनिधि सदन दोनो ही दो वडे लोकत त्रीय देशो के निम्न सदन हैं। दोनो म सगठन एव दानितया की दृष्टि से महान् अतर है। कुछ समान ताएँ भी है। अमेरिको प्रतिनिधि सदन ब्रिटिश कॉम स समा की ही सन्तान है एव मुनरो के शब्दो म अपने वशजा की छाप प्रतिनिधि सदन पर स्पष्ट है। 34 कॉम स समा प्रतिनिधि सदन की तुलना म वडा सदन है । कॉम स समा समस्त व्यावहारिक कार्यो के लिए ब्रिटिश ससद है जो विधिक हप्टि से सप्रमु होती है एव उसे विधायी मामलो मे अतिम धनित प्राप्त है । लेकिन प्रतिनिधि सदन की यह स्थिति नही है। वित्त विधेयक दोनो ही सदनो म सवप्रयम प्रस्तुत किये जाते है परन्त कॉम स समा की जनके सम्बाध म अन्तिम शक्ति प्राप्त है। लेकिन प्रतिनिधि सदन द्वारा पारित नित्त-विधेयक को सीनेट बदल सकती है। गैर-वित्तीय विधेयको के सम्बाध मे लाडसमा को अधिक से अधिक 1 वय की विलम्बकारी शक्ति प्राप्त है। लेकिन प्रतिनिधि सदन एवं सीनेट की शक्ति इस सम्बंध म समान है । कॉम स समा को अपना काय-काल बढाने एवं घटाने का अधिकार है। लॉडसभा की शवितयो एवं स्वरूप म उसे परिवतन की शक्ति प्राप्त है। लेकिन अमेरिकी कांग्रेस के उच्च सदन सीनेट म राज्यो को प्राप्त समान प्रतिनिधित्व से विचत नहीं किया जा सकता। कॉमन्स समा की माति प्रतिनिधि सदन का कायकाल घटाया या बढाया नही जा सकता है । ब्रिटेन म ससदीय व्यवस्था के कारण कायपालिका कॉम स समा के प्रति उत्तरदायी होती है। शासन को कॉम स समा को विघटित करने की माँग का अधिकार होता है। लेकिन अमेरिका मे शक्ति-पृथक्करण के सिद्धात के कारण प्रतिनिधि सदन के प्रति कायपालिका उत्तरदायी नहीं होती है और न कायपालिका द्वारा व्यवस्थापिका को विघटित ही किया जा सकता है। मुतरो के अनुसार कॉम स समा मे प्रतिनिधि सदन की तुलना मे अधिक व्यवस्था एव शाति का वातावरण होता है। प्रतिनिधि सदन म काय की सभी को शीध्रता दिखायी देती है। उपस्थिति भी अपेक्षाकृत कम होती है। केवल कुछ सदस्य ही काय रत रहते हैं। अ त म, यह कहा जा सकता है कि एक सदन विशुद्ध रूप से अग्रेज है तो दूसरा अमेरिकी और प्रत्यक की अपनी-अपनी आदर्ते एव रुचिया हैं।**

प्रतिनिधि सदन सीनेट की तुलना में कमजोर सदन है। इसके अग्रलिखित कारण है

³⁴ Munro Government of Europe, p 171

³⁵ Munro op at , p 172

324 | आधृनिक शासनतात्र

 सीनेट की भाँति प्रतिनिधि सदन को कायपालिका अर्थात नियक्तिया एव सचियो सम्बंधी शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं।

(2) उसका कायकाल सीनट की अपेक्षा बहुत बम है । प्रथम वप म तो अधिकारा सदस्य अपने दायित्वा ने प्रति सजग ही नही हो पात और दूसरे वप क आरम्म से ही निर्वाचन की भाग दौड़ म लग जात हैं।

(3) प्रतिनिधि सदन की काय पद्धति दुरुह है। सदस्या के पास विचार विमय के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। अत सदन के अधिकाश निगय अविवकपूर्ण होते हैं।

(4) प्रतिनिधि सदन सीनेट की तुलना में बहुद सदम है। राजनीतिक दला की इतनी अधिक चाले होती हैं कि सदस्यगण अपने दायित्वों को मलीमांति सम्पादित नहीं कर पात । सीनेट में दलीय अनुशासन अपक्षाकृत कम हाता है ।

(5) लास्की के अनुसार सोनट को जितना सम्मान प्राप्त है उतना प्रतिनिधि समा की प्राप्त नहीं है। 38 अ य देशा म निम्न सदन का सदस्य होना गौरवपूण माना जाता है जबकि अमेरिका म सीनेट की सदस्यता की राष्ट्रपति के मित्रमण्डल की सदस्यता स भी अधिक महत्व दिया जाता है। अमेरिका म अनुमवी एव योग्य राज नीतिना की आकाक्षा हमेशा सीनेट के सदस्य वनने की हाती है। सीनेटर अधिकाशतया

प्रतिनिधि सदम के सदस्या की अपेक्षा अधिक योग्य भी होते हैं। (6) प्रतिनिधि सदन सामूहिक रूप से जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता। पेटरमन³⁷ के शब्दा म यद्यपि "यह सदन अमेरिकन जीवन की जडाऊ तस्वीर है

एव इसके सदस्य विभिन्न राज्या की जनता होते हैं पर तुवास्तविक बात यह है कि वे स्थानीय वाता का प्रतिनिधित्व करत हैं, न कि राष्ट्रीय हित का । उनका निर्वाचन यहुत कम समय के लिए स्थानीयता के नियमानुसार होता है जिससे कि वे दुवारा भी

प्रतिनिधि चन जा सके।' (7) अमेरिकी प्रतिनिधि सदन सबस खर्चीला होता है। यही इसकी दुबलता के कारण हैं। इनक कारण अमेरिकी प्रतिनिधि सदन विश्व के सबसे कमजोर निम्न सदना मे गिना जाता है। लास्की अने अनुसार प्रतिनिधि सदन उन कृत्या को सम्पा दित करने म नितात असफल रहा है जिनकी उससे अपेक्षा थी । वह एक महान

राष्ट के लिए अनुपयकन सदन है। रूस की सुप्रीम सोवियत³⁰ का निम्न सदन—सघ सोवियत

रूस की सधीय व्यवस्थापिका-सुप्रीम सीवियत-द्विसदनात्मक है। सघ सीवियत (Soviet of the Union) निम्न सदन तथा राष्ट्रजातीय सोवियत (Soviet of

Laski The American Democracy, p 89 36 Patterson op cit p 371

³⁸ Lasks op at , p 79

³⁹ राज्य सत्ता का सर्वोच्च अस-अनच्छेद 30

Nationalities) उच्च सदन है 10 सघ सोवियत के सदस्या को सावियत नागरिको द्वारा निर्वाचित किया जाता है। प्रत्यक सदस्य तीन कास प्रत्यकाओं का प्रति निर्मिद्द करता है। 14 सघ सोवियत सम्मूण राष्ट्र का प्रतिनिधित्य करता है अर्थात यह जन प्रतिनिधित्य करता है। अपनी रचना म यह प्रजात श्रीय देशा के निम्न सदमा से निम्त्रता है। यह किसी राष्ट्र-जाति (Nationality) या हित का पृथक रूप से प्रतिनिधित्य नहीं करता। सचीय शासन म द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका एक अनिवाय आव-स्थकता है, लेकिन सावियत रूस म द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका एक अनिवाय आव-स्थकता है, लेकिन सावियत रूस म द्विसदनात्मक विषय से उचित कारण स्थीकार नहीं निया जा सकता। सोयियत रूस सहर्याप्ट्रजातिय से है तथा स्टानिन के अनुसार ऐसे देश को अनक राष्ट्रजातिया के प्रतिनिधिया के अभाव प्र मास्को म सर्वोच्च शासन का चलना असम्भव है। अत द्वितीय सहन—राष्ट्रजातीय सेवियत (Soviet of Nationalities)—की व्यापना की गयी है।

दोना सदना का कायकाल चार वप है ⁶⁸ और दोनो ही सदन समान रीति से सावमीम मताधिकार पर गुप्त मतदान हारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित होते है तथा एक साम विघटित होते है। प्रत्येक 18 वर्षीय वयस्क स्थी नावरिक—स्नी तथा पुरप-का मतदान का अधिकार प्राप्त है। सर्वाच्च सोवियत की सदस्यता के लिए प्रत्येक 23 वर्षीय प्राप्त का मित्र नार्वाच्च माम माम से सम्बत्त है। साक्तीय अधिकारियो एव सैनिकों को भी सर्वाच्च सोवियत के सदस्य होन का अधिकार है। भारत, सयुक्त राज्य अमरिका द्वा ग्रेट जिटन में ऐसी स्विधा नहीं है।

बोनो सदना को विधि निर्माण सम्बन्धी समान शिक्तियों प्राप्त हैं व तथा उनके सामाय बहुमत से विध्यक का पारित होना आवश्यक हाता है। कि तिसी विध्यक का परित होना आवश्यक हाता है। कि तिसी विध्यक के प्रकार परे तोना सदनों में मत्रे ने बों अवस्था में उसे वोनो सदनों की मध्यक्ता प्रिमित (Conchistion Committee) के पास निष्य के लिए भेज दिया जाता है। यदि मध्यक्ष्यता समिति विद्याद को हुक करने में अवकस्य रहती है या समिति व्याप्त मत्रावित हुन से कोई एक भदा सहुमत नहीं होता तो दोनो मदना म पुन उस पर विचार होता है। यदि दोनो सदा फिर मी एकमत नहीं होते तो प्रेसीडियम सर्वोच्च सोवियत को मम कर देती है और नवीन निर्वाचनों का आवेदा दिया जाता है। वोनो सदना में सम्मेलन एक साथ आहूत होते ह तथा दोनों के सवावसान भी एक साथ ही होते हैं। कि

सघ सोवियत की शक्तिया

सप सोवियत रूस के शासन का सबसे शक्तिगाली अग है । इसे व्यापक

⁴⁰ Article 32

⁴¹ Article 34 42 Article 36

⁴³ Article 37

⁴⁴ Article 39

⁴⁵ Article 47 46 Article 42

विधायो, गवधानिक, सामवातक, आधिक, मायिक एव निवासक मध्यापी प्रतियो

प्राप्त है । इसरी स्थिति बहुत कुछ प्रिटिंग समय जना है ।

मियान म अनुसार सेष माविषा को मुरक्षा, पर्शनिक मासल, विश्नो ब्यागर, कर तथा राजस्त, आधिक योजनार निर्मा काल त्रोय सेषा था प्रश्या का स्वय म प्रामिल परना, यातायात के साधा, मुद्रा, वोमा, त्रम, अधिकाय, कृषक एवं औषा निव संवदाा, गाविष्य एवं जीवा निव संवदाा, गाविष्य एवं जीवा निव संवदाा, गाविष्य एवं जीवा निव संवदाते के स्वया म विधि बनान का अधिकार प्राप्त है। म इस्त अतिरिक्त मियान म दोना मदना क 2/3 बहुमत से मधाधन सम्ब है। मंग के मित्र के पोषणा तथा विग्ना सा सिष्य परना सच सावियत वा हो बाव है। मण के मित्र चण्डल को निवृष्ति से सेतिरिक्त के मित्र के सिष्य के स

समोक्षा—सम सायियत ने दोना सदना ने सन वय म दा बार अति अल्प-मात अधात नेयत एन सप्ताह या 10 दिन ने लिए ही हान हैं। " इस अल्पकात म सप सोयियत के लिए अपनी सिक्या का मलो-मीति प्रयोग करना सम्मन नहीं है। अत सम सीयियत के लिए अपनी सास्त्रिया का मलो-मीति प्रयोग करना सम्मन नहीं है। अत सम सीयियत उन विधेयका का नेवल अनुमादन मात्र करती है जिह साम्यवादी दत पहले ही स्थोष्ट्रत कर पुत्र हो। " विराधी दत के अमान म सीयियत सातन की को को को प्रमावसाओं आलोचना भी सम्मन मही है। इसके विपरीत, साम्यवादी लेखका का यह दाना है कि सप सीयियत राज्य सीकि है। इसके विपरीत, साम्यवादी लेखका का यह दाना है कि सप सीयियत राज्य सीकि है। इसके विपरीत, साम्यवादी लेखका का यह दाना है कि सप सीयियत पाज्य सीकि है। इसके विपरीत, साम्यवादी लेखका का यह दाना है कि सप सीयियत पाज्य सीकि है। इसके विपरीत, साम्यवादी लेखका का यह दाना है कि सप सीयियत स्थाप पाज्य सिक्य करती है और सीवियत वनता के मध्य आतृत्व,

⁴⁷ Article 14

⁴⁸ Article 146 49 Article 56

⁴⁹ Article 56 50 Article 48

⁵¹ Article 105

⁵² Article 114

⁵³ Article 65

⁵⁴ Article 14 (k)

⁵⁵ Article 46

⁵⁶ Refer to Carter and Others Government of Somet Union, 1954, p 105

मित्रता एव सहवार म योग देती है। यह जनमत ना मायर-वन्त्र है। मध्य सोवियत ना सदस्य 'जनता ना सेवर तथा उसका सःदाबाहरू होता है।' जनता उसका प्रत्याहाहन रर सनती है। व परेवर राजनीतिण नहीं होत अवितु समाजवादी उत्पादन आदि संसम्बर्धित होते हैं। यह सदन साम्यवादी गुट एव निदसीय व्यक्तिया का सरक्षार है तथा प्रमाजवाद र जनूनवी गमठ यादा की स्थित म है।

लेक्नि सप सावियत की वास्तविक स्थिति पर कुछ विचारका न इससे मिन्न मत ब्यक्त रिय हैं। आँग एव जिक ने अनुसार सावियत समाचार-पत्रा म प्रकाशित विचारा र अनुसार विचार विमरा र सदन वे रूप म सच साविवत सफल हुई है लेकिन परिचम के अनव विचारका वे लिए इस मूल्याकन को स्वीकार करना सम्मय नहीं है। वय म दो बार रचल 10 दिन के लिए हान वाले सत्र इस बात का प्रमाण हैं कि सप सोवियत विधेयका ना प्रस्तावित एवं विचार करन, बादविवाद, संशोधन एव मतदान पर उतना समय व्यय नही बरती जितना कि अय विधानमण्डला म होता है । सोवियत सब म विधेयन सामा यत मा त्रिया, साम्यवादी दलया जाय विसी निकाय द्वारा प्रमाणित क्यि जात हैं। पश्चिमी दशा की हुन्टि म सुध सावियत का 'विचार-विमय या सदन' नहा यहा जा सरता । यह पश्चिमी व्यवस्थापिका ने सदना की भौति भी नहीं है लेकिन इसका यह अध नहीं है कि सावजनिक मामला म इसका आवश्यक प्रमाय नहीं होता है। र जिसमन टाउस्टर के अनुसार सथ सोवियत यद्यपि सिद्धान्त म सर्वोच्च विधि निर्माण का अम है, परात आकार म वहद निवाय होने एव यप म उसके अल्परालीन सन्नो के होन के कारण अभी तक वह प्रधानत अनुमोदन एव समयन करने वाले सदन के रूप म ही काय करता रहा है। इसका मूख्य नाय समय या अव-सर के अनुकल शासकीय नीति को प्रतिनिधि सदन के रूप म स्वीकृत करना रहा है। 8 कताडा की कॉमन्स सभा

पनाडा की ससद दिसदनात्मक है। प्रथम सदन को कॉम स समा (House of Commons) तथा द्वितीय सदन को सीनेट (Senate) कहते हैं। काम स समा के सदस्या का वयस्क मताधिकार पर 5 वय के लिए जनता द्वारा निर्वाचन होता है। कॉम स समा को प्रधानमात्री के आग्रह पर कनाडा के गवनर-जनरस द्वारा अवधि के पूच भी

⁵⁷ In the western sense, Supreme Council of U S S R may not be a truly deliberative body—certainly it does not conform to the pattern of western legislative bodies—but it should not be assumed that it does not exercise atleast a reasonable amount of influence in the public affairs of the Soviet Union."

⁻Ogg and Zink Modern Foreign Governments 1956, p 860

^{58 &#}x27;Theoretically the supreme sowet is the sole legislating organ has so far operated primarily as a ratifying and propogating body. Its thic purpose appears to be periodically, or occasion demands, to lend the voice of approval of a representative —Julian Towstor Folitad Power in the USSR, pp. 262 263

विषटित किया जा सकता है। इसकी सदस्य-सस्था स्थिर नहीं है। प्रति 10 वर्ष वाद जनसस्था के आधार पर उसकी सदस्य सस्था में सक्षीधन या परिवतन होता रहता है। तेकिन बिटिश नोंच अमेरिका एक्ट (The British North America Act) के हारा स्पूर्वेक (Quebec) प्रात के प्रतिनिधियों की सस्था 65 निश्चित है जो अपरिवतनीय है। शेष प्रात्त के अतिनिधियों की सस्था के निर्धारण के विष् स्विधान में सहया का जनकी के उत्तिनिधियों की सह्या के निर्धारण के विष् सिद्धान में सह्या के निर्धारण के विष् सिद्धान में सिद्धान के अनुसार अय्य प्रात्तों को उनकी जनसस्था के अनुपात में उतने ही स्थान प्राप्त होंगे जितने कि क्यूबक को (65 स्थान) उसकी जनसस्था के अनुपात में प्राप्त होंगे हैं।

1952 ई के नवीन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन कॉमस समा की

सदस्य सख्या 265 है। विभिन्न प्राता की सदस्य सख्या निम्नवत है श्रीटोरियो (Onterio) के 85, बयुबेक (Quebec) के 65, नोबोस्कोशिया

(Novo Scotia) के 12, प्रिस एडवड हीए (Prince Edward Islands) के 4, पू चुताबिक (New Bruinshwick) के 12, मनीतोबा (Manitoba) के 14, विदिध कीलन्दिया (British Columbia) के 22, सस्त्रेचवान (Saskatchewan) के 17, अलबर्टी (Alberta) के 17, पूजाउण्डलवड (New Foundland) के 7 तथा उत्तर प्रिवसी के पूरुत (Yukan) को गैरी मेकेजी जिले (Mackenzie Distinct) के 1-1 सदस्य होते हैं। 1952 ई से पूज कॉम स संज्ञा को सदस्यता [81 थीं।

दोना सदनो की शिक्तिया समान है। वित्त विषेयक काम स समा म हो सदप्रम प्रस्तुत किये जाते हैं। येप सभी विधेयक सवप्रथम किसी भी सदन म प्रस्तुत किये जाते हैं। येप सभी विधेयक सवप्रथम किसी भी सदन म प्रस्तुत किये जाते हैं। प्रत्येक विधेयक का दोनो सदन। से पारित होना आवर्षयक है। ग्रेट विटंक में मिति वित्त-विधेयक वेवक शासन हाय ही प्रस्तुत किय जाते है, किसी अक्तिगत सदरय होरा नहीं। मित्रमण्डल के अधिकाश सदस्य कोता है। मित्रमण्डल के विरद्ध काम स समा म अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने का अथ मित्रमण्डल के विरद्ध काम स समा म अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने का अथ मित्रमण्डल का पत्त होता है। अधिकाश महत्वपृण विधेयक निम्न सदन (कॉम स समा) म ही प्रस्तुत किय जाते हैं। इंगलण्ड की मीति कनाश्च में भी विषेयकों को प्रथम वाचन, दितीय वाचन, सिर्मित स्तर, प्रविवेदन-स्तर एव तृतीय वाचन की अवस्थाओं को पार करना पड़ता है। क्षेप म कताश की काम स समा ब्रिटिश कियाओं को पार करना पड़ता है। क्षेप म कताश की काम स समा ब्रिटिश कियाओं को पार करना पड़ता है। स्वेप म कताश की काम स समा ब्रिटिश कियाओं को पार करना पड़ता है। स्वेप म कताश की काम स समा विटिश कियाओं के पार करना पड़ता है। स्वेप म कताश की काम स समा व्रिटिश कियाओं का प्रमुख अपिकरण है। इसकी प्रात्ति स्तर है। यह वाचन की अवस्थित का प्रमुख अपिकरण है। इसकी प्रात्ति स्तर है। विधि निर्माण विद्य, कायपातक एव अप स्वर्ण है। इसकी प्रमुख विद्या किया निर्माण विद्य, कायपातक एव वाच की स्वर्ण म इसकी प्रमित्र स हो विधि निर्माण विद्य कायपातक एव वाच का स सुलन कर है। इसकी प्रमुख विद्या कर राजनीतिक जीवन का स सुलन व कर है। इसकी स्तर्या होती ही स्वर्ण मान स्वर्ण स्वर्ण स स्वर्ण होती है। यह देश कर राजनीतिक जीवन का स सुलन व कर है। इसकी

⁵⁹ The House of Commons 'is the real driving force just as the House of Commons is in England and for the same reasons
—Bryce Modern Democracies, Vol I, 1929, p 514

वित्त पर नियन्त्रण है। कायपालिया के निर्माण एव विषटन की दाक्ति इसम निहित है। अत यह दलोय संघय का केंद्र है। ⁶⁰

आस्ट्रेलिया का प्रतिनिधि सदन

आस्ट्रेलिया की द्विसदर्भीय संघीय व्यवस्थापिका थे निम्न सदन को प्रतिनिधि सदन (House of Representatives) कहते हैं। इसकी सदस्य सस्या प्रारम्भ म 75 यी लेकिन जब 122 है। सिवधान के अनुसार प्रतिनिधि सदन को कुल सदस्य सर्था सीनट की सदस्य सर्था सीनट की सदस्य सर्था सीनट की सदस्य प्रतिनिधि सदन सर्था की दुगुनी होनी चाहिए और किसी भी राज्य के 5 से कम सदस्य प्रतिनिधि सदन म नहीं होने चाहिए। सदन का कायकाल 3 वप है। सीनट के लिए मतदान करने की जो योग्यताएँ हैं वही प्रतिनिधि सदन के लिए मी है। 1924 के अधीन आस्ट्रेलिया म अनिवाय मतदान का सुत्रपाठ हुआ है। मत का प्रयोग न करने वाले मतदान को 10 दिलिय से 2 पीण्ड तक जुर्माना देना पडता है। फलस्वस्य आस्ट्रेलिया म अनिवाय मतदान का सुत्रपाठ हुआ है। मत का प्रयोग न करने वाले मतदान को 10 दिलिय से 2 पीण्ड तक जुर्माना देना पडता है। फलस्वस्य आस्ट्रेलिया म 70 से 90 प्रतिवात तक मतदान होता है।

दोना सदनों की विक्तियाँ समान है, केवल वन विषेयक सवप्रयम प्रतिनिधि सदन म ही प्रस्तुत कियं जा सकते हैं। सीनट को वित्त विषेयकों को पूणक्ष्येण अस्वीकार करते का तो अधिकार है लेकिन उत्तमें वह संशोधन नहीं कर सकतो। मिनण्डल मामूहिक रूप से प्रतिनिधि सदन के प्रति उत्तरदायी होता है और उसी के प्रसाद पन त प्रतिकृत है। सदस्यों को शासन से प्रक्त एव पूरक पूछने अथवा सुचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार है। प्रतिनिधि सदन आलाचना करने वाला सदन है और वाह्य जनमत की अधिकार है। प्रतिनिधि सदन अका प्रोक्त एव निव प्रस्ताद तथा अदिव्यास प्रतिकृति का साधन है। सदन में काम रोक्ते एव निव प्रस्ताद तथा अदिव्यास प्रतिकृति के माध्यम संजन-प्रतिनिधियो द्वाराख्यत का प्रयान वनता की किता होने पर सित प्रमण्डल का प्रवान हो। तदा या अविव्यास का प्रस्ताद तथा तथा हो। ते सो प्रतिकृति का साथ स्वान व प्रति होने पर मित्रमण्डल का प्रस्ता तथा है। प्राद्व के अनुसार आल्ट्रेलिया में "समद राज्ञीतिक कार्यों का के ह है। कायपालिका का पूरा स्वानी है। किसी निवेधाधिकार का उस पर प्रतिवाध के उन्हों है। सबद में लोकिय सदन (प्रतिनिधि सदन) की शक्ति सर्वाण्य है क्यांन वह कायपालिका को वनाती एव विभावती है तथा वित्त के सम्बद्ध म उस स्वान प्राप्त है। "

स्विट्जरलेण्ड का प्रथम सदन-राष्ट्रीय परिपद

िष्यस सपीम द्विसदनात्मन व्यवस्थापिका के निम्न सदन को राष्ट्रीय परिषद (National Council) कहते हैं। यह जनता का सदन है। इसकी सदस्य-सस्था मे समय-नमय पर जनसम्या के अनुपात म परिवतन होता रहता है। सविधान द्वारा

^{60 &}quot;The House controls finance and since it has the making and un making of the Executive Ministries, is the centre of party strife."

—Bryce Ibid. p. 514

⁶¹ Bryce Modern Democracies, Vol II, 1929, p 199

इसकी सदस्य सरया निश्चित नहीं की गयी है। प्रित 10 वस परचात मतगणना के आवार पर प्रत्येक केण्टन की जनसङ्या के अनुसार उसका प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्या की सख्या निर्धारित की जाती है। लेकिन सिवधान म यह सुस्पष्ट है कि प्रत्यक पूण या व्यर्ढ केण्टन को राष्ट्रीय समा म कम से कम एक प्रतिनिधि भेजने का अविकार अवस्य प्राप्त होगा। इस व्यवस्या का मुख्य उद्देश प्रत्येक केण्टन के जाता के हिता का सर क्षण करना है। वन (Berne) नामक केण्टन के 1940 ई की जनगणना क अनुसार उत्तर है। वन (Berne) नामक केण्टन के 1940 ई की जनगणना क अनुसार उत्तर है। वन (Berne) नामक केण्टन के 1940 ई की जनगणना क अनुसार उत्तर है। विकार केण्टन ऐसे हैं जिनका केवन एक एक प्रतिनिधि है। प्रत्येक बीस वर्षीय वयस्क हिवस नागरिक को राष्ट्रीय परिषद के सदस्यो के निर्वाचन का अधिकार है। सदस्य प्रत्यक्ष मतवान द्वारा समानुषातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के का आधार पर मिर्चाचित होते है। दिवटजरलण्ड के निर्वाचन कोनो का निर्धाण काम पालिका न करके व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। 1920 ई के पूब राष्ट्रीय परिषद का कार्यकाल 3 वध था लेकिन उसके पश्चत 4 वध हो गया है। राष्ट्रीय परिषद का कार्यकाल 3 वध था लेकिन उसके पश्चत 4 वध हो गया है। राष्ट्रीय परिषद की सदस्यता व्यवहार म प्राय स्थायी है क्योंकि अधिकाश सदस्य पून निर्वाचित होते रहते है।

स्विस सपीय व्यवस्थापिका—फेडरल असेम्ब्रली—के दोना सदना की सिक्त्या समान है। कोई विषेयक किसी भी सदन म सवप्रथम प्रस्तुत किया जा सकता है। सपीय परिपद (Federal Council) अर्थात सपीय कायपालिका के सदस्यों को दोनो सदनों में बठने का अधिकार है और वे दोनों ही सदना के प्रति उत्तरदायी होते हैं, वेकिन उनका कायकाल निश्चत है।

विश्व को कोई अय व्यवस्थापिका स्वित संयीप समा की माति उनेक एव विमिन प्रकार के दायित्वो का सम्यादन नहीं करती । फेडरल असेम्बली विधि निर्माण के क्षेत्र म सप्रमु है । इसके अतिरिक्त वायिक जाय व्यय लेल की स्थीकृति, तिष्रधान में सक्षाध्म, नथीन संधीय पदो का निमाण, राजस्व एकर करना, मुख्य नेनापित की नियुक्ति तथा संधीय परिषद एवं संधीय यायात्वय के यायाधीश्चा को निवाधित करते की शक्ति फेडरल असेम्बली को प्राप्त है । केण्टमो द्वारा परस्पर तथा विदेशों के साथ की जान वाली संधिया को संधीय असेम्बली ही अनुसोदित करती है। देश की मुख्या स्वत नता एवं तदस्यता की रक्षा एवं अनुरक्षण के लिए उसे उचित काय बाही करने का अधिकार है । युद्ध की घोषणा एवं शांति स्थाधित करते, केण्टमो की क्षेत्रीय सुरक्षा एवं स्वत नता वी रक्षा, राष्ट्रीय केना का नियनण एवं निरोहण तथा सामृहिक एवं व्यक्तिगत दाना प्रदान करने सन्व यो व्यापक अधिकार उसे प्राप्त हैं। प्रशासिक कार्यों के निरोक्षण एवं प्रशासकीय मामला म संधीय समा को अन्तिम सिक्त प्राप्त है। राष्ट्रीय परिषद संधीय अक्षेम्बली का निम्न सदन है। फलस्वरूप इन

^{62 1919} ई म सवप्रयम समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का सूत्रपात किया गया है। 63 स्विस स्त्रिया को मताधिकार 8 फरवरी, 1971 ई को प्रदान किया गया है।

⁶⁴ Hans Huber How Sutst etland is Governed 1946 p 45

शक्तिया के उपमोग म उसे उच्च सदन के समान ही शक्ति प्राप्त है। उच्च सदन की सदस्य-सच्या राष्ट्रीय परिषद से कम होती है अत राष्ट्रीय परिषद की इन शक्तियों के प्रयोग मे भूमिका निर्णायक होती है। सिद्धात में दौना सदनों की शक्तिया समान होन पर भी व्यवहार मे राष्ट्रीय परिपद अधिक शक्तिशाली है। इसका प्रमुख कारण यह पारणा एव विश्वास है कि राष्ट्रीय परिषद जनता का प्रत्यक्ष रीति से प्रतिशिधत्व करने वाला सदन है। स्मरणीय है कि राष्ट्रीय परिपद द्वारा कुछ कतव्यो को द्वितीय सदत--राज्य-परिषद के सहयोग से सामृहिक रूप से सम्पादित किया जाता है, यथा--संघीय परिषद के सदस्या, फेडरल टिब्युनल के "यायाधीशो, स्विस परिसंघ के अध्यक्ष, सेनापति एव चा मलर का निर्वाचन दोना सदना के सबूक्त अधिवेशन मे ही होता है। सदत में सम्मान, सम्यता एवं अनुशासन पाया जाता है 165 जास्ट्रेलिया की भाति दोनो सदना की शक्तिया समान हैं। व्यवहार में द्वितीय सदन जो केण्टना का प्रतिनिधित्व करता है, दोना सदो म कमजार सदन है। क्षमताबान एव महत्वाकाक्षी व्यक्ति राष्ट्रीय परिषद के ही सदस्य होना पसन्द करते हैं। दोना सदना में किसी प्रश्न पर मतभेदो को हल करने सम्बन्धी कोई व्यवस्था उही है। लेकिन न सी अधिक मतभेद होते हैं भीर न वे गम्मीर ही होते हैं। इसका कारण यह है कि राज्य परिषद के सदस्य द्वितीय सदन से कम अनुदारवादी नहीं होत । विधान सम्बंधी असिम निणय की शक्ति जनता के हाथों में होती है। कि विधानमण्डल के सदस्या में स्विस चरित्र की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। वे गम्भीर एव चत्र होते हैं कि तु भावक नहीं। " सदना म उपस्यिति नियमित होती है और सदस्यगण समय का पूरा ध्यान रखते हैं।88 सदनो में निवाचना में राजनीतिक दल फास व इगलैण्ड की तुलना में बहुत कम भाग लेते हैं। दोना सदना म दलो का संगठन कठोर उही है। अ सदनो म समितियों की स्थिति अमेरिकी कांग्रेस की माति शक्ति एवं महत्व की नहीं है । व्यक्तियत विधि निर्माण अपेक्षाकृत कम होता है। ° स्विटजरलैण्ड म विराधी दल भी उग्र नही है, न सत्तारूढ दल ही पदा पर अपना एकाधिकार रखना चाहता है। विरोधी दलो द्वारा प्रशासन ने कार्यों म बाधा नही डाली जाती और इस प्रकार आय ससदीय देशो की माति प्रगति र्य के पत्रा को अवस्द्र नहीं किया जाता । सदस्यगण दसीय हप्टि की अपेक्षा राष्ट्रीय भावना स विधेयको पर विचार करत है। "र स्विस विधानमण्डला मे उस प्रतिमा का अत्यात अभाव है जा 1920 ई तक उनम परिलक्षित होती थी। इसके अतिरिक्त दोना सदना की अय कोई आलोचना सम्भव नहीं है। वे क्षमतापूचक अपना काय करते हैं।

⁶⁵ Hans Huber op cut, p 47

Bryce Modern Democracies, Vol I, 1929, p 386 lbtd, p 387 lbtd, p 389 lbtd, p 390 lbtd, p 391 66 67

⁶⁸ 69

⁷⁰ Ibid , p 392 71

332 | आधुनिक शासनता प्र

आचरण तथा व्यवहार के श्रेष्ठ स्तर को व कायम रखते हैं, जनता का उह सम्मान प्राप्त है तथा वे कायपालिका से सहयोगपूबक काय करते हैं।

साम्यवादी चीन की व्यवस्थापिका-राष्ट्रीय जनवादी काँग्रेस

साम्यवादी चीन के सविधान (1954 ई) के अ तगत एकसदनीय व्यवस्थापिका का निर्माण किया गया है। इस राष्ट्रीय जनवादी काग्रेस (The People's Congress) कहते है। यह साम्यवादी चीन की राज्य-शक्ति का प्रयोग करने वाला सर्वोच्च एवं एकल अग है । 3 उसके सदस्यगण, जि ह डेपुटीज (Deputies) कहा जाता है, प्राता, स्वशासित क्षेत्रा, के द्रीय शासन के अधीन नगरपालिकाआ, संशस्त्र सनामा एव विदेशा में निवास करने वाले चीनी नागरिकों म स चुने जात है। सदस्पता का काय काल 4 वप है। कौग्रेस अपने कायकाल से दो माह पूर्व विघटित हो जाती है तथा काँग्रेस की स्थायी समिति (Standing Committee) द्वारा आगामी कांग्रस के प्रति-निधियों को निर्वाचित करने की व्यवस्था की जाती है। काग्रेस के कायकाल का विशेष परिस्थितियो म आगामी काग्रेस के प्रथम सन तक के लिए नढाया जा सकता है।

यह एक वृहद सस्या है। द्वितीय काँग्रेस की सदस्य सरया 1959 ई म 1,226 थी। तृतीय काँग्रेस की सदस्य सस्या 1964 ई म 2,848 हो गयी थी। वय म काँग्रस का केवल एक ही सन होता है जो स्वायी समिति के द्वारा आहत किया जाता है। स्यायी समिति द्वारा आवश्यकता के समय अथवा 1/5 प्रतिनिधिया द्वारा माग करने पर कांग्रेस के विशेष सत्र आहत किये जा सकते हैं।

काय एव शक्तिया-राष्ट्रीय जनवादी काग्रेस को व्यापक शक्तियाँ प्राप्त है। इसे अपने दो तिहाई बहुमत से सविधान मे सशोधन करने की शक्ति है। इसे विधि निर्माण, सविधान के पालन हतु निरीक्षण, चीन के राष्ट्रपति एवं उप राष्ट्रपति के निर्वाचन, चीन के अध्यक्ष की सिफारिश पर प्रधानम ती एवं प्रधानम त्री के परामश पर मित्रमण्डल के सदस्या की नियुक्ति क अधिकार प्राप्त है। यही सर्वोच्च यागालग क अध्यक्ष एव प्रधान प्रोक्यूरटर का निर्वाचन करती है। 'राष्ट्रीय जायिक योजनाआ के सम्बाध म यही अतिम निणय करती है। काग्रेस राष्ट्रीय रक्षा समिति के उपाध्यक्ष एव सदस्यों की नियुक्ति के सम्बाध में निणय करती है। कांग्रेस ही राजकीय बजट एव वित्त सम्बाधी प्रतिवेदना की जाँच करती है तथा उन्ह स्वीकृत करती है। यही युद्ध एव शाति सम्बाधी मामला का निषय करती है सावजनिक क्षमा प्रदान करती है तथा प्राता, स्वनासित क्षेत्री एव केंद्र प्रशासित नगरपालिकाओ की सीमा एवं दर्जे की

सविधान के अधीन काग्रस का साम्यवादी चीन व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधान-म त्री, उप प्रधानम त्री, मित्रमण, समितिया के अध्यक्ष, राज्य-समिति कं महाम त्री,

स्वीकृति दती है ।"

⁷² Ibid, p 393

⁷³ Articles 21 and 22

⁷⁴ Article 27

राप्ट्रीय रक्षा समिति के अध्यक्ष एव सदस्य, जनवादी यायालय के अध्यक्ष एव प्रधान प्रोक्यरेटर का पदच्यत करन के अधिकार प्राप्त हैं।

समीक्षा—चीन की जनवादी राष्ट्रीय किंग्रेस का निर्वाचन परिचमी लीक-तानिक देद्दों की मीति नहीं होता है। चीन म व्यापक मताधिकार है तेकिन सूपित-वन तथा नित्त विरोधी वग एव तत्वा को मतदान वा अधिकार नहीं है। प्रतिनिधिय क्षेत्रीय एव सामूहिक दोना हिता के आधार पर चुने जाते हैं। अत प्रतिनिधियण अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित होते हैं तथा विभिन वर्गी एव हिता को असमान प्रति-निधित प्राप्त है। सदन य क्षेत्रीय एव वर्गीय हिता के प्रतिनिधित्य की व्यवस्था है।

राप्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के निर्वाचन पूणक्ष्येय स्वतः न नहीं है। विरोधी दल के जमाव के कारण सोवियत रूस की भाति व्यवहार में अधिकतर स्थानों के लिए एक ही उम्मीदवार खडा होता है। उम्मीदवारों की नामजदयी पर साम्यवादी दल के अधिकारियों मा नियानण होता है। उम्मीदवारा की एक सूची होती है और वे सभी अभिवार्य रूप मा साम्यवादी दल के सदस्य होत है या उसकी विचारपारा से सहानुभृति रखते है।

स्यायी समिति (The Standing Committee)

चीन की राष्ट्रीय काग्रेस की स्थायी समिति एक स्थायी निकाय है । इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महाम नी एव काग्रेस द्वारा निर्वाचित अस्त सदस्य होते हैं । स्थायी समिति अपने कार्यों के लिए राष्ट्रीय काग्रेस के प्रति उत्तरदायी होतो है तथा उसके समक्ष अपने कार्यों का प्रतिचेदन प्रस्तुत करती है। राष्ट्रीय काग्रेस को स्थायी समिति के सदस्या के प्रत्याचतन की द्यांक्ष प्राप्त है। इसका कायकाल 4 वप है।

काय—स्यायी समिति के काय हैं—राष्ट्रीय काग्रेस क प्रतिनिधियो का

निर्वाचन करना, उसके अधिवेशन आहूत करना, विधियों की व्याख्या करना, आह्न दिनयों प्रचारित करना तथा राज्य समिति (State Council), जनवादी यायावय एवं प्रोनपूरेटर के कार्यों का निरीक्षण करना, सिवधान एवं विधि विरुद्ध आदेशों व निणया को रह करना, प्रांतो, क्षेत्रों एव नगरपालिकाओं के अनुचित निणया को अस्वी कृत करना उप-प्रधानों, मित्रयों, आयोगों के अध्यक्षां, जन-न्यायालय के उपाध्यक्ष, "यायाधीशों एवं प्रोवपूरेटरों आदि को निमुक्त एवं पदच्युत करना, राजदूता की निमुक्त एवं उनकी वापसी का निणय करना, सिध्यों को स्वीकार एवं अस्वीकार करना, सिनक, राजनीतिक एवं अय उपाधिया व पदा को व्यवस्था करना, झमादान, पूण या अधिक वीनक मतीं का निणय करना सैनिक कानूनों को नियाचित करना, जनवादी काग्रेस के सनावसान करना स्व सम्बन्धी निणय करना, आदि।

उपरोक्त कार्यों के विवरण से स्पट्ट है कि स्थायो समिति द्वारा विधायो, काय पालक "यायिक एव प्रशासनिक सभी प्रकार के दायित्व सम्पादित किये जात हैं। यह सीवियत रूस की प्रेसीडियम की साति है। वेकिन सीवियत प्रेसीडियम का अध्यक्ष राज्य का अध्यक्ष होता है जबकि स्थायो समिति का अध्यक्ष राज्य का अध्यक्ष नहीं होता। वे नि का अध्यक्ष नहीं होता। वेने में राज्य का अध्यक्ष नहीं होता। वेने में राज्य का अध्यक्ष जवाबी गणत न का समापित होता है। सीवियत प्रेसीडियम को सहार होता। वे ने सीवियत प्रेसीडियम को सहारक होता के उच्च कथान की नियुक्ति एव उन्ह प्रबन्धत करते का अधिकार प्राप्त है जबकि की न गणराज्य को स्थायो समिति को यह शक्ति सिदान्तत

प्राप्त नहीं है, यद्यपि व्यवहार में उसने इस शक्ति का प्रयोग किया है।

अपने कही हैं, पंचान व्यवहार ने वारत को अपने किया है।

कुछ वित्यमें के सद म म बीन की स्वायी सिनित सोवियत कस की प्रेतीडियम
से भी अधिक शिक्त्याली है, जैंसे—(1) प्रेतीडियम की माति मित्रया की नियुक्ति
एव पदच्छुति के लिए स्थायी सिनिति को प्रधानमात्री एव जनवादी काग्रेस के अप
समयन की आवस्यकता नहीं है। (2) राष्ट्रीय जनवादी काग्रेस सिव्धान म बांग्यत की
सिक्त्यों को स्थायी सिनिति को सीप सकती है। क्ली सिव्धान म प्रधान को देश कोई
समयन की आवस्यकता नहीं की स्थान कालती है। क्ली सिव्धान म प्रधान कोई
स्थान में स्थान के स्थान की स्थान कालती है। क्ली सिव्धान म प्रधान में है आपोभी की
नियुक्त कर सकती है। सोवियत सथ की प्रेतीडियम की ऐसी कोई शिक्त प्राप्त नहीं
है। स्थायी सिनिति कोग्नेस के प्रति उत्तरदायी होती है और उत्तके समझ प्रतिवदन भी
प्रस्तुत करती है लेकिन स्थायी सिनिति की स्थित व्यवहार म के प्रीम
है और कांग्रेस
उत्तकता अनुगमन करती है तथा उसके द्वारा निमित एव स्वीकृत विधिया का अनुसम
पन मात्र करती है।

भारत का निम्न सदन-लोकसभा

मारतीय गणराज्य की संघीय ससद द्विसदनात्मक है। निम्न सदन को लोकसमा (Lok Sabha or the House of the People) एवं उच्च सदन को राज्यसमा (Rayya Sabha or the Council of States) कहते हैं। ⁶ लाकसमा जनता का सदन है। राज्यसमा संघ के घटको ना प्रतिनिधित्व करता है।

लोक्समा की अधिकतम सदस्य सख्या 525 निश्चित की गयी है। राज्या के विभिन्न निर्वाचन-क्षेत्रो से अधिकतम 500 सदस्य एव के द्र-प्रशासित क्षेत्रा से अधिक-तम 25 सदस्यों के निर्वाचन का सविधान में विधान है। " 1963 ई के पूव तक के द प्रशासित क्षेत्रा के प्रतिनिधिया की अधिकतम सस्या 20 थी। इस वय पाण्ड्चेरी को प्रतिनिधित्व देने के लिए 20 के स्थान पर अधिकतम सख्या 25 कर दी गयी है। ⁸ सर्विधान द्वारा प्रत्येक राज्य की सदस्य-सख्या का प्रथक रूप से उत्लेख नहीं किया गया है अपित सामा य सिद्धा त का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक राज्य को उसकी जनसच्या के अनुपात में लोकसमा म प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इस प्रकार के प्रतिनिधित्व का आधार समान होता है। प्रत्येक सदस्य अधिकतम पाच लाख व्यक्तिया का प्रति-निधित्य करता है। यही प्रतिनिधित्व की समानता का सिद्धान्त निर्वाचन क्षेत्रों के सादभ म भी भाय है। प्रत्यक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व समान होना चाहिए। अनुच्छेद 81 (2) (व) के अनुसार प्रत्येक राज्य को क्षेत्रों म इस प्रकार विमाजित करना चाहिए कि प्रत्येक क्षेत्र समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे । प्रत्येक नदीन जनगणना के परचात निर्वाचन क्षेत्रों का पूनगठन होता है एवं इस सम्बंध में ससदीय विधि द्वारा व्यवस्था का विधान है। 79 1951 ई के मतगणना के आधार पर ससद ने 1952 ई मे परिसीमन आयोग अधिनियम पारित किया या ।80 1956 ई मे राज्य-पुनगठन के समय राज्य पुनगठन अधिनियम के अन्तगत उक्त अधिनियम की व्यवस्थाओं को निरस्त कर दिया गया एव एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया और इस आयोग को ससदीय एव राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रा म संशोधन एवं परिवधन का अधि-कार दिया गया 181 परिगणित जातिया एवं जन-जातियों के लिए लोकसमा में स्थान मुरिन्त है। प्रारम्भ मे यह व्यवस्था केवल 10 वप के लिए थी। परात दो बार क्रमश 10-10 बप के लिए सर्विधान में संशोधन के माध्यम से वृद्धि की गयी है 162 लोक-समा के निवाचन के लिए सविधान-समा ने पृथक एव साम्प्रदायिक निर्वाचन को अस्वीकार कर दिया था। आग्ल-मारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व के अमाव म राप्ट्रपति को दो सदस्य मनोनीत करन का अधिकार है। 83

राज्य पुत्रमञ्ज के पश्चात लोकसभा की सदस्य सख्या 500 वी एव 1957 ई के सामाय निर्वाचन के उपरात लोकसभा की सदस्य-सख्या म कोई विद्वि नहीं

⁷⁷ अनुच्छेद 81 (अ) एव (व)।

^{78 14}वा सर्वेद्यानिक संशोधन, 1963 ई ।

⁷⁹ जन्चेंद 82

⁸⁰ The Delimitation Commission Act, LXXXV of 1952

⁸¹ Sections 40 to 48, States Reorganisation Act, 1950, No XXXVII, pp 22-25

⁸² अनुच्छेद 334 एव 8वा सवधानिक सद्योवन, 1959 ई एव 23वा सर्शोधन,

⁸³ अनुच्छेद 331

336 । आधनिक शासनतात्र

हुई है। 1967 के सामा य निर्वाचन के पदचात लोकसना म 521 सदस्य थ। 1970 इ के मध्याविध निर्वाचना के बाद गठित पांचवी लावसमा म 518 सदस्य हैं।

कायकाल

लाक्समा का कायकाल 5 वय है। इस अवधि के पूर्व भी विषटित किया जा सन्ता है। सकट-काल म इसकी अवधि ससदीय विधि द्वारा एक बार म । वय क लिए बढायी जा सकता है लेकिन सकट बाल की समाप्ति के बाद किसी भी अवस्था म 6 माह सं अधिक की बद्धि नहीं की जा सकती। 84

लोकसमा की सदस्यता के लिए निम्न अहताएँ निधारित की गर्मी है-(1) भारतीय नागरिक हो और उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। (2) उन समस्त मोग्यताजा को पूण करता हो जो ससदीय विधि द्वारा निर्धारित की गयी है। 8 सेकिन कोई भी व्यक्ति दोना सदना का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता और न ससद या किसी राज्य व्यवस्थापिका का ही एक साथ सदस्य हो सकता है 164 पागल, दिवालिया, सभ एव राज्य शामन में लाम के पद धारण करन वाले. विदशी, भारतीय नागरिकता का परित्याग नरके किसी अय देश की नागरिकता स्वीकार करने वाल तथा किसी ससदीय विधि की व्यवस्था द्वारा अयोग्य घोषित किय जान वाले व्यक्ति लोकसमा की सदस्यता के अधिकारी नहीं हो सकता 187 लाकसमा के सदस्या का निवाचन प्रत्यक्ष रोति से वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। प्रत्यक 21 वर्षीय भारतीय नागरिक को जो विधि द्वारा एवं सविधान के अन्तगत मताधिकार से विचत नहीं है, लोकसमा के निर्वाचन म मत देन का अधिकारी होता है।

अधिकार एव शक्तियाँ

भारतीय लोकसमा की विधायी, वित्तीय, निर्वाचन, कायपालक, सविधानिक एव अ'य शक्तिया निम्नवत है

विधामी शक्तियां-विसी विधेयक की पारित होने के लिए लोकसभा द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। वित्त विधेयक लोकसमा म ही सवप्रथम प्रस्तुत किये जाते हैं। 89 गैर वित्तीय विधेयक दोना म से किसी भी सदन म सवप्रयम प्रस्तुत किया जा सकता है। अदोनो सदनो में किसी विधेयक के सम्बन्ध म मतभेद होने पर या अप सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकार करने या एक सदन द्वारा दूसरे सदन से किसी विधेयक को प्राप्त होने क पश्चात 6 माह का समय व्यतीत हा जाने पर राष्ट्रपति

⁸⁴ Article 83 (2)

⁸⁵ Article 84

⁸⁶ Article 101

⁸⁷ Article 102 88 Article 326

Article 109

⁸⁹ 90 Article 107

को दोना सदनो का समुक्त अधिवेशन आहूत करने का बिधकार प्राप्त है। समुक्त अधि-वेशन मे दोना सदना के उपस्थित सदस्या के बहुमत से यदि विधेयक पारित कर दिया जाता है तो वह विधेयक ससद द्वारा पारित माना जाता है। ⁸¹ लेकिन यह व्यवस्था धन-विधेयको के सम्बन्ध मे नहीं है। लोकसमा की सदस्य सरया अधिक होने के कारण समुक्त अधिवेशन मे उसकी इच्छानुसार विषयो का स्वीकृत होना अनिवाय है और यही लोकसमा की स्वित है।

वित्तीय शक्तिया—लोकश्वमा को राज्य के वित्त पर वास्तिविक नियायण प्राप्त है। वित्त विश्रेयक सवप्रयम लोकसमा म ही प्रस्तुत किये जाते है। लोकसमा श्वारा वित्त-विश्रेयक के पारित किये जाने पर वह राज्यसमा के समझ अरक्ती सिफारिश के तिए प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसमा को वित्त विश्रेयक को अरकी सिफारिश के तिए प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसमा को तीन्न विद्येयक स्वीति स्वीति स्वीति स्वीति स्वीकार मांकसमा को लोग देना चाहिए। ¹⁹² राज्यसमा की सिफारिशा को स्वीतार या अस्वीकार करने का अधिकार लाकसमा को है एव तवनुरूप विश्येयक सस्वीतार पारित माना जाता है। यदि 14 दिन के अन्दर राज्यसमा वित्त विश्येयक की न तो पारित करती है और न लोगती है तो विश्येयक लोकसमा द्वारा जिस रूप में पारित किया गया है उसी रूप म सबद द्वारा पारित मान त्या जाता है। ¹²³ अत राज्यसमा को वित्त विश्येयक के सम्बन्ध म के केवल 14 दिन की विलम्बकारी प्रतित प्राप्त है। विदिश्व लोडसमा को वित्त विश्येयक के सम्बन्ध म के नेवल 14 दिन की विलम्बकारी प्रतित प्राप्त है। विदिश्य लोडसमा को वित्त विश्येयक के सम्बन्ध म 1 माह की विलम्बकारी प्रतित प्राप्त है। अनुदान की माथा एव करो की स्वीकृति पर सोकसमा का एका-प्रवार है।

कायपालिका पर नियंत्रण सम्बंधी शक्तियौ—तोशसभा का यह अत्यंत महत्वपूण काय है। के द्रीय मित्रमण्डल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तर-दायों होता है " जब लोकसमा के प्रसाद पयत ही मित्रमण्डल सत्तास्ट रह मनता है।" सिद्धातत उत्तरदायित्व मही नियंत्रण निहित होता है एवं नियंत्रण और उत्तर-दायित्व को पूचक करना असम्भव है। लोकसभा का नियायण के द्रीय मित्रमण्डल को अनुत्तरदायों होने से राकता है, फलस्परूप मित्रमण्डल सब्द सजय रहता है। लोग-समा के सदस्य शासन के कार्यों की सूचना प्राप्त वरके शासन पर नियात्रण रखते है। प्रस्त पुद्रक प्रवत्त पुद्रकर सदस्यों द्वारा शासकीय नीति एवं वार्यों के सब्देय में सूचना प्राप्त की जाती है तथा नीति की आसोचना करके शासन पर नियात्रण रखा जाता है। सोक्समा वाद विवाद का सदन है। सदस्यों द्वारा किसी मी थिपय

⁹¹ Article 108

⁹² Article 109 (2)

⁹³ Article 109 (5)

⁹⁴ Article 75 (3)

⁹⁵ Article 74 (3)

338 | आधुनिक शासनतात्र

पर वाद विवाद की माग की जा सकती है। अनुदान की माँग पर विचार के समय धातः के कार्यों की तीव्र आलोचना की जाती है। महत्वपूण जाकिस्मक घटना घटित हों पर काम रोको प्रस्ताव उपस्थित किये जा सकते है। नि दा प्रस्ताव एव अविद्याध प्रस्ताव उपस्थित किये जा सकते है। नि दा प्रस्ताव एव अविद्याध प्रस्ताव उपस्थित करके शासन को अपने काय एव नीति के लिए उत्तरदायों ठहराय जाता है। इन प्रस्तावों के पारित होने पर शासन को त्यागपत्र देना पडता है। राष्ट्र वित्ते के मायण के पश्चात उस पर वाद विवाद के अवतर के माय्यम से विरोधी रक्ष को शासन की नीतियों की समीक्षा एव आलोचना करने का श्रेष्ठ अवसर प्रान्त होता है। विगत 25 वर्षों म लोकसमा मे काग्रेस दल का सुनिश्चित बहुमत रहा है एव सुड विरोधी रक्ष का मारतीय सत्वदीय जीवन मे अमाव रहा है। फिर भी तोकसमा म माव विवाद का स्तर सत्तीपजनक एव प्रवत्तनीय रहा है। प्रति विन आभा मण्टे का समय वाद विवाद के लिए निश्चित होता है। यह जनता की शिकायतों की अभिव्यक्ति के लिए उचित अवसर होता है। बार्षिक वजट के समय प्राय प्रयक्ष विमाग के कार्यों की समालीचना की जाती है तथा मित्र्यों को अपने कार्यों एव नीतियों के सम्ब ध में सदस्य को सन्तुष्ट करना पडता है।

सवधानिक शक्तियां—सिष्धान में सदीयन करने का लोकसमा को अधिकार प्राप्त है। अधिकाश सवधानिक सलिधन प्रस्तावा को दोनों सदना के द्वारा पृथक पृषक रूप में कुल सदस्य-सरया के स्पष्ट बहुमत एवं उपस्थित सदस्या के दो तिहाई बहुमत से पारित होना आक्ष्यक है। सधीय व्यवस्था से सन्धिक्षत प्रावधाना में उत्तर रीति के अतिरिक्त राज्या के विधानमण्डला की स्वीकृति भी आव्यवस्त्र होती है। के अतिरिक्त राज्या के विधानमण्डला की स्वीकृति भी आव्यवस्त्र होती है। कि भारतीय लोकसमा को ब्रिटिश कॉम संस्त्र की माति इस सन्धि में अनियानिक शिवत प्राप्त नहीं है। न यह सीवियत स्व की सुप्तीम सोवियत की मीति सवैधानिक सदीभान के सदम में एकाधिकार का प्रयोग करती है। इस सदम में उत्तरी विद्यात विधान की मीति सवैधानिक सदीभान के प्रतिविधि सदन जैसी है। भारतीय लोकसमा की सिंव भाग की कुछ महत्वपूण व्यवस्थाओं से सक्षीधन का सामा य विधि से अधिकार प्राप्त है। भारतीय ससद सामा य विधि पारित करके भारतीय सप म नवीन राज्या की सामित कर सकती है, एवं उनकी सीमाओं, क्षेत्रों, नामों आदि में परिवतन या विमाजन कर सकती है। व्य उनकी सीमाओं, क्षेत्रों, नामों आदि में परिवतन या विमाजन कर सकती है। व्य उनकी सीमाओं, क्षेत्रों, नामों आदि में परिवतन या विमाजन कर सकती है। व्य उनकी सीमाओं, क्षेत्रों, नामों आदि में परिवतन या विमाजन कर सकती है। व्य उनकी सीमाओं, क्षेत्रों, नामों आदि में परिवतन या विमाजन कर सकती है। व्य उनकी सीमाओं, क्षेत्रों, नामों आदि में परिवतन या विमाजन कर सकती है। व्य

निर्वाचन सम्बन्धी तथा 'यायिक एवज्यशक्तिया---राष्ट्रपति एवउप-राष्ट्रपति के निर्वाचन म लोकसमा का सन्निय योग हाता है । लोकसमा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक-मण्डल के सदस्य होते हैं 1⁸⁸ उप राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसमा एव राज्य

⁹⁶ এনুদর্ভ্রব 368

⁹⁷ अनुच्छेद 2 और 3

⁹⁸ Article 54

समा के सदस्या द्वारा समुक्त अधिवेशन म किया जाता है। 19 राष्ट्रपति के विरुद्ध महा-नियोग का प्रस्ताव किसी एक सदन द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है एव दूसरा सदन उसकी जाज करता है। 100 उप-राष्ट्रपति को पदन्युत करने सम्बन्धी प्रस्ताव ना राज्यसमा द्वारा पारित होने पर लोकसमा द्वारा अनुसमयन आवश्यक है। 101 इसके अति रिक्त सर्वोच्च यायालय अथवा उच्च यायालय के यायायीशो को पदन्युत करने के सम्बन्ध मे लोकसमा को अधिकार प्राप्त है। योगी सदना द्वारा पुथक-पुथक रूप मे इस आद्या के स्पष्ट बहुमत एव उपस्थित धरस्यो के दो तिहाई बहुमत स प्रस्ताव पारित करके प्रतिवेदन करने पर राष्ट्रपति यायाधीशो को पदन्युत कर सकता है। 100 लोकसमा को अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को निर्वाधित एव पदन्युत करने के अधिकार प्राप्त है। उपने सदस्यो तथा बाहर के किसी भी व्यक्ति को सदन के विशेषाधिकार का हनन करने के अपराध में दण्ड देने का अधिकार भी उसे प्राप्त है। 102 विमिन्न सकटकालीन घोषणाओं को जारी रखने के लिए ससद की स्वीकृति

समिक्षा— मारतीय लोकसमा कई अयों में बिटिय कांम स समा से समानता रखती है लेकिन उसकी माति सप्रमु नहीं है। इसका कारण भारतीय सिवधान का लिखित एव सपीय होना है। बिटिय कांम स समा हो व्यवहार में विटिय सक्त है। उसके द्वारा पारित विधियाँ माविक वुनरींक्षण के क्षेत्राधिकार से मुक्त है। द्विटिय ससद हारा सविधान म सरलतापुषक सबीधन सम्मव है। गैर विलीय विधेयकों के समद प्रमु में लाइतमा को केवल । वप का विलम्बकारी निपेधाधिकार प्राप्त है। मारतीय लोकसमा को राज्यसमा की तुलना में अधिक सक्ति प्राप्त है। विशेष ना सक्ती है। स्विप्त सामाय-काल म केवल सधीय सुची के विध्या पर ही विधि बना सकती है। स्विप्त सामाय-काल म केवल सधीय सुची के विध्या पर ही विधि बना सकती है। स्विप्त सोधाय विधियाँ मौलिक अधिकारों या सविधान की किसी धारा का असित्रमण करती हैं ने "यायालय द्वारा वे अवधानिक घोषित की जा सक्ती हैं।

भारतीय लोकसमा की प्रमुख आलोचना निम्नवत है

(1) लोकसभा नी निर्वाचन पद्धति जनमत को ठीक प्रकार स अभिन्यक्त नहीं करती।

(थ) सविधान निर्माताओं ने लोकसभा के निर्वाचन के सम्बाप म समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अस्त्रीनार कर दिया या न्याकि वे उसे ससदीय धामन के अनुकूत नहीं मानते थे। इससे स्थिर धासन के बनने की सम्भावना समाप्त हो जाती

⁹⁹ Article 66

¹⁰⁰ Article 61

¹⁰¹ Article 67 (2)

¹⁰² Articles 124 (4) and 217 (1) (6)

¹⁰³ Articles 93 and 94

है। सदन म अनेक राजनीतिन दला के अस्तित्व की सम्मावना मी वड़ जाती है। इसके अतिरिक्त यह पद्धित जिटल है एव अतिशित मतदाताला क अनुरूप नही है। ससरीय सासन की सफलता के लिए द्विदलीय पद्धित एक अनिवाय आवश्यकता है। अत लाक समा के सदस्या का एवल सदस्यी निर्वाचन क्षेत्रा से सावमीम वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन होता है। 1961 ई के द्विसदस्यी निर्वाचन (उम्मलन) अधि नियम के पूव कुछ क्षेत्र द्विसदस्यी थे। यह वे निर्वाचन क्षेत्र से जहाँ से परिपणित जातियों एव अनुसुचित वर्षों के सदस्य चुने जाते थे। अय द्विसदस्यी निर्वाचन क्षेत्र समाप्त हो गये हैं।

(अर) इस निर्वाचन पद्धति का एक अ य दोप यह है कि निर्वाचन म प्राप्त कुल मतो के अनुपात म सदन में स्थान प्राप्त नहीं होते हैं। मारतीय लोकसमा के चार सामा य निर्वाचन एक एक मध्याविध निर्वाचन म दिष्ट व कॉम स समा के निर्वाचन सम्याधी कमियो एक दोषा को दुहराया गया है। प्रथम निर्वाचन (1951 52) म लोकसमा के 489 स्थाना म से काँग्रेस को 363 व्यात 74% स्थान प्राप्त हुए ये लोकसमा के 489 स्थाना म से काँग्रेस को 363 व्यात 74% स्थान प्राप्त हुए येलाक उसे कुल मता के केवल 44 प्रतिचात मत ही प्राप्त हुए ये ने इस निर्वाचन म समाजवादी वल को 10 प्रतिचात मत प्राप्त हुए ये लेकिन उस केवल 3 प्रतिचात स्थान ही प्राप्त हो सके थे। द्वितीय एव ततीय निर्वाचना में मी इसी महानी को दोहराया गया है। यदि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया होता तो इन निर्वाचना है। यदि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया होता तो इन निर्वाचना है। यदि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया होता तो इन निर्वाचना होता जो भारतीय ससदीय धासन प्रणाली के जीवन म स्वय एक अभिगाप वन जाते।

(इ) लोकसभाम दो सदस्य आग्ल मारतीय मनोनीत किये जात हैं। सिंध धान के 25 वप के पश्चात भी इस प्रकार के सरक्षण की अब काई आवश्यक्ता नहीं उही है।

(2) सुटढ एव उत्तरदायी विरोधी दल का अभाव भारतीय ससदीय सासन प्रणासी की एक महत्वपूण समस्या है। इसके अभाव म सत्तारुढ दल का एक प्रकार से दलीय अधिनायनत्व स्थापित हो जाता है। मारत में कांग्रेस दल का केंद्र एवं राज्या में प्रयम 15 वर्षों म एकछत्व राज्य रहा है। केंद्र से तो विगत 25 वर्षों कांग्रेस ही पदारुढ है। ऐसी स्थिति में सत्तारुढ दल को जनता द्वारा हटाये जाने का भय हो नहीं है और सासन के भी व्यवहार में अनुत्तरदायी हा जाने की आसका है।

(3) ब्रिटन की माति भारत में भी मिनमण्डलीय अधिनायकरव की स्थापना हुई है। ससद मिनमण्डल का अनुषर बन थयी है। सुदृढ विरोधी दल का अभाव इस अधिनायकरव के लिए माग प्रशस्त करता है। भारत के ससदीय जीवन म विरोधी दल मां उनकी सरया के आधार पर नहीं औंका जाना चाहिए। इधर कुछ वर्षों म थिरोधी दलों ने अपनी श्वरिक ते बिचक समता का प्रदश्न किया है। प्रतिनिधि सदन के रूप में लोक्समा का मृत्याकन कठिन है। इसके सदस्य कम शिक्षित हैं। उन्हें उन सुविधाओं का भी अभाव है जिनके कारण वे अधिक सिक्स रूप से काम कर सकते हैं। उन्हें गम्मीर विन्तन के लिए अवसर प्राप्त नहीं है और न शोध की सुविधाएँ ही प्राप्त हैं। अपने निर्वाचका से उनका सम्ब य टूट जाउा है। 194

फ्रेंच गणराज्य के निम्न सदन

त्तीय क्रव गणराज्य (1875 1940) को द्विस्तात्मन व्यवस्थापिका---राष्ट्रीय समा (National Assembly)----क निम्म सदन को चेम्बर ऑफ डेपुटीन (Chamber of Deputies) एव उच्च सदन को सीनट की सजा दी गयी थी। दोनो सदनो की विधि निर्माण सम्बधी शक्तिया समान थी। १०० नेकिन विद्य विधेयक चेम्बर ऑफ डेपुटीन में ही सवप्रथम प्रस्तुत किये जा सकते थे। सीनेट को विद्य विधेयक को अस्विक्त करते का अधिकार था और व्यवस्थार में उसने इस अधिकार का पर्याप्त क्रिया था। मिनमण्डल दोनो सदनो के प्रति उत्तरसारी होवा था। वेम्बर आफ डेपुटीन की निर्वाचन 21 वर्षीय वयस्क फेच पुरुप सवदाताओ द्वारा 4 वप के लिए होता था। राष्ट्रपति को चेम्बर ऑफ डेपुटीन का विधेटन सीनेट की अनुमति स करने वर अधिकार पा। सार्वपति स्वरूप अधिकार पा। सार्वपति स्वरूप अधिकार पा। सार्वपति को चेम्बर ऑफ डेपुटीन का विधेटन सीनेट की अनुमति स करने वर अधिकार पाप सार्वपति सार्वपति स्वरूपति सार्वपति सार्व

¹⁰⁴ Palmer and Tinker Leadership and Political Institutions in India, pp 135 136 quoted by D C Chaturvedi Indian Government and Politics, 1973, p. 218

¹⁰⁵ Ogg and Zink Modern Foreign Governments, 1956, pp 447 48

¹⁰⁶ The most distinctive characteristic of the Constitution of the Fourth Republic is its concentration of almost absolute power in the hands of one chamber, the National Assembly '—Carter, Ranney and Hertz The Government of France, 1956, Ind ed p 116

पचम भेच गणराज्य (1958) की ससद द्विसदनात्मक है। राष्ट्रीय समा (National Assembly) निम्न सदन है, सीनेट (Senate) उच्च सदन है। राष्ट्रीय समा ने सदस्य प्रत्यक्ष रीति से एव सीनेट के सदस्य अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित होते है। राष्ट्रीय समा का प्रत्येक सदस्य एकल सदस्यी निर्वाचन क्षेत्र से इहरे गुप्त मतदान में बहुमत प्राप्त करने पर निर्वाचित घोषित किया जाता है। प्रथम गुप्त मतदान म ही जिह स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है वे उसी मे विजयी घोषित कर दिये जाते हैं। द्वितीय गुप्त मतदान की व्यवस्था केवल उन्ही निर्वाचन क्षेत्रा में होती है जहां किसी भी प्रत्याशी को प्रथम मतदान में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता। द्वितीय मतदान म सामा य बहुमत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को ही विजयी घोषित किया जाता है। इस मतदान व्यवस्था का उद्देश्य उग्रवादिया को हटाना एव मध्यवनीय प्रत्याशिया को सफल बनाना है। मतदाताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मध्यमवर्गीय प्रत्याशियों का द्वितीय मतदान म सहायता दें। नवम्बर 1958 ई के निर्वाचन म यह आशा पूण भी हुई। इस निर्वाचन म साम्यवादियों को नेवल 10 स्थान मिले ये जबकि चतुर्य गणराज्य की राष्ट्रीय सभा मे उन्ह 145 स्थान प्राप्त हुए थे और वह सदन म सबसे वडा राजनीतिक दल था। पाँचवें मणराज्य म राष्ट्रीय समा की सदस्य-सख्या घटाकर 465 कर दी गयी है।

¹⁰⁷ The French National Assembly (was) not simply one organ of government among many taking its place side by side with the Council of the Republic the Cabinet and the Presidency It is the supreme agency to which all others are subordinate "—Carter, Ranney and Hertz op sit, 1956, Ind edn. p 116

दोना सदना की विधि निर्माण सम्बाधी शक्तियाँ समान है। वित विध्यक के सम्बाध म सीनेट की कुछ अधिकार प्रदान किये गये हैं। यदि राष्ट्रीय समा वित्त विद्युपक के प्रस्तुत दिया जान क 40 दिन के बादर प्रक्षम वाचन पर ही कीई निष्य नहीं के पाती तो सीनेट की वित्त विद्युपक पर विचार करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। किसी विध्यक पर दोना सदना म मठभेद होन पर समान मरमा म दोना सदने के सदस्या से गठित एक समुक्त समिति के विचाराण विचारमपद विध्यक का अपनुत किया जाता है। यहाँ यह सम्बाधित है वि समिति द्वारा प्रस्तावित हुत दाना सदना के समक्ष साधन द्वारा है प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ यह किया जाता है। यहाँ यह किया जाता है और समिति द्वारा प्रस्तावित हुत दाना सदना के समक्ष साधन द्वारा है। प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत का सक्ताव दोनो सदना को स्थीकाय नहीं है अथात् नकुक सनित के प्रस्तुत प्रस्तुत कर सकता है और दोना सदना के वाचनो (reading) इ प्रस्तुत प्रस्तुत कर सकता है और दोना सदना के वाचनो (reading) इ प्रस्तुत प्रस्तुत कर सकता है और दोना सदना के वाचनो (reading) इ प्रस्तुत प्रस्तुत कर सकता है और दोना सदना के वाचनो (reading) इ प्रस्तुत प्रस्तुत कर सकता है और दोना सदना के वाचनो (reading) इ प्रस्तुत प्रस्तुत कर सकता है और दोना सदना के वाचनो (reading) इ प्रस्तुत प्रस्तुत कर सकता है और दोना सदना के वाचनो (reading) इ प्रस्तुत प्रस्तुत कर सकता है और दोना सदना के वाचनो (reading) इ प्रस्तुत प्रस्तुत कर सकता है और दोना सदना के वाचनो (reading) इ प्रस्तुत प्रस्तुत कर सकता है और दोना सदना के वाचनो (reading) इन प्रस्तुत कर सकता है और दोना सदना के वाचनो (reading) इन प्रस्तुत कर सकता है और सीनिट का कोई अधिकार प्रस्तुत नहीं हुन्य है।

जारर रक्षा कर कर ज्यान स्ट्रन

का नायकाल 5 वय है। प्रधानमन्त्री के परामश्च पर राष्ट्रपढि द्वारा इसे विषटित किया जा सकता है।

नायरलैण्ड म प्रतिनिधि सदन प्रधानम त्री को मनोनीत करता है। अप निधी देश की व्यवस्थापिका को यह अधिकार प्राप्त नही है। प्रधानमात्री द्वारा मनोनीत मन्त्रिया को प्रतिनिधि सदन स्वीकृत करता है। वित्त विधेयको पर इस पूण नियानण प्राप्त है। वे केवल निम्न सदन म ही प्रस्तावित किय जा सकते हैं। प्रतिनिधि सदन द्वारा पारित वित्त विधेयक 21 दिन के अन्दर विधि वन जात हैं, भसे ही उच्च सदन इस अवधि मे उह स्वीकार वरे अथवा न करे। सविधान म संशोधन प्रस्तावित करने का इस सदन को एकाधिकार प्राप्त है। मिन-परिषद इसी सदन के प्रति उत्तरदायी हाती है। किसी वित्त-विधेयक के सम्बाध म यह विवाद होने पर कि वह वित्त विधेयक है अथवा नही, प्रतिनिधि सदन का निणय अतिम होता है। उसके इस निणय के विरुद्ध विशेषाधिकार समिति म अपील की जा सकती है। इस विशेषाधिकार समिति मे दोनो सदना के समान सदस्य होते ह और सर्वोच्च न्यायालय का यायाघीश इसका अध्यक्ष होता है। गैर-वित्तीय विधेयकों के सम्बाध में दोनो सदना की शक्ति समान है। ऐसे विधेयक किसी भी सदन मे प्रस्तावित किये जा सकते हैं तथा दोना सदना हारा पारित होने पर ही वे विधि वनते हैं। यदि प्रतिनिधि सदन द्वारा पारित गर वितीय विधेयक सीनेट द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है तो प्रतिनिधि सदन पुन उस विधे यक को सीनेट के द्वारा अस्वीकृत होने के 90 दिन म पारित करक सीनेट के पास भेज देती है एव 90 दिन बीत जाने के पश्चात अर्थात 91वे दिन वह विधेयक स्वत ही पारित माना जाता है। प्रधानमात्री यदि विधेयक की आवश्यक प्रमा णित कर देता है एव राष्ट्रपति मिन-परिषद की सम्मति प्राप्त करके उस अनुमोदित कर देता है तो प्रतिनिधि सदन द्वारा 90 दिन की अविधि में भी कमी की जी सकती है।

दोनो सदनो द्वारा पारित होने के पश्चात विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षरा के लिए भेजा जाता है। सामा यत राष्ट्रपति नियेघाधिकार का प्रयोग नहीं करता । वैर दिसीय विधेयको एव सर्वेधानिक सरोधिय के प्रस्तावों को मिन्न-परिपद के परा मरा पर वर्षोंक स्थानास्य की सम्मति हेतु भेजने का राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च स्थानास्य की सम्मति हेतु भेजने का राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च स्थानास्य की सर्वानिकता सम्ब की अभागा अभिमत 30 दिन के अद्यु सा सा स्थानिक सा पारित हो। सर्वोच्च स्थानास्य विधेयक को अध्वानिक सामाता है तो राष्ट्रपति

उसे अपनी स्वीकृति प्रदान नही करता ।

जापान की डाइट (व्यवस्थापिका)

1889 ई के पूच जापान मं साम तशाही थी। राजा को देवता के समान पूजा जाता या पर तु उसे बहुत अधिक शक्ति प्राप्त नहीं थी। राजकुमार इटो द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर 1889 ई म जापान में प्रथम सविधान का निर्माण हुआ था। इसे मोजो सविधान (The Meiji Constitution) कहते हैं। यह अधिकाशत प्रसा (Prussia) के सविधान पर आधारित या और इसकी 76 में से 46 धाराएँ प्रसा के सविधान से प्रभावित थी। प्रधानम नी राजा के प्रति उत्तरहामी होता था एव प्रसा के नमूने पर ससदीय शासन की स्थापना की गयी थी। यह जापान का प्रथम विखित सविधान थी निकन प्रारम्भ से ही इसके विकास में अपसमयाने ना स्वयम्प्रीमका निमायी थी। आधानी व्यवस्थापिना को साम्राज्यी डाइट (Imperial Diet) की सामा प्रदान की गयी। इसमें पीयर समा (House of Peers) एव प्रतिनिधि सदन (House of Representatives) नामक दो सदन थे।

उच्च सदन—पीयर समा—की सदस्य सक्या 409 थी। इनम से 200 सदस्य साम त वग म से बशानुगत आधार पर नियुक्त किये जाते थे। इनमे राजवश के राज-कुमार एवं उच्च सामत भी शामिल थे। 125 पीयर जीवन मर के लिए प्रधानमानी के परामश पर सम्राट हारा नियुक्त किये जाते थे। सर्वाधिक कर देने वाल धनिक वग हारा भी कुछ सदस्य निर्वाचित किये जाते थे जिड्ड सम्राट हारा 7 वय के लिए पीयर समा का सदस्य निर्माक किये जाता थे। 100

प्रतिनिधि सदम निम्न या प्रथम सदन या । इसकी सदस्य सङ्या 450 के आसपास यो जो 122 बहुसदस्यी निर्वाचन क्षेत्रा से निर्वाचित किय जाते थे । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से अधिकत्तम 5 सदस्य निर्वाचन क्षेत्र से १¹⁰⁰ 'एक मतदाना एकमत' के सिद्धात पर गुप्त मतदान स सदस्य का निर्वाचन होता था। प्रतिनिध सदन का कायकाल 4 वप या सिकन उसे उसकी अवधि क यूव भी सम किया जा सकता था। 1925 ई को निर्वाचन विधि द्वारा सरक्योग पुरुप मताबिकार की क्यवस्था की गयी और प्रत्येक 25 वर्षीय जापानी वृद्ध्य की मतदान का अधिकार दिया गया था। प्रतिनिध सदन की रात्तिमा अधिकार सिक्या अध्यापन से स्वत्य जापानी वृद्ध्य की मतदान का अधिकार दिया गया था। प्रतिनिध सदन की राक्तिया अध्याधक सीमित थी। वित्तीय मामतो में सखद (डाइट) का कम निय नण या। बिद डाइट वर्ष्ट को पारित करने में असफल रहती थी तो विगत वप के स्वीकृत कर आधार पर प्राप्तन को प्रसासन का अधिकार प्राप्त पा। 1931 ई के पश्चात प्रशासन में सनिक अधिकारियों के प्रमुख म बद्धि हो गयो थी। 1941 ई म सविधान का स्वरूप अस्पविक प्रशासनी हो यथा था।

नवीन जापानी सविषान (1946 ई) के ज्योन डाइट (Diet) को राज्य सिक की सर्वोच्च जग घोषित किया गया है। इस सविषान के निर्माण पर अमेरिकी प्रमाव स्पप्ट है। दितीय विश्व-मुद्ध म पराजित होने के परचात जमस्कि प्रेरणा से जापान के नवीन सविषान का निर्माण हुआ है। इस सविषान के अ तथा जापान म देवी राज-तेन का परित्यान करके अन-प्रमुख को स्थापना की गयी है। सम्राट के कर्तव्य केवल अपचारिक हैं। अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध भी में जापान में सदेव के लिए शक्ति के परित्यान

¹⁰⁸ Ogg and Zink *p cit , p 957

नी पोषणा की है और जल, यल एव नम सनाजा ना न रखने ना निशय निया है। व्यापक मौलिक अधिकारा का स्वीकार निया गया है। स्वरूप म सविधान कठोर है।

इस नवीन सविधान के ज तगत जापानी व्यवस्थापिका—उाइट (Diet)—
िहसतनात्मन है। प्रतिनिधि सदन (House of Representatives) प्रथम सदन है और
काउ सलर सदन (House of Councillors) द्वितीय सदन है। प्रतिनिधि सदन की
सदस्य सस्या 466 है। सदस्या वा 4 वय के लिए ययस्क माधिकार के भागाय पर
निर्वाचन होता है। मतदान की यूनतम आयु 20 वय है। जापानी इतिहास म प्रथम
वार महिलाओ को भी मतदान का अधिकार दिया गया है। उच्च सदन क सदस्य
—काउ सलर—नी जनता द्वारा प्रस्यक्ष रीति से ही चून जात हैं। इनकी सस्या 250
है। काउन्सलर सदन म बसानुमत आधार पर कोई सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकता।
100 काउन्सलर सिला से तथा 150 प्रीकेक्चरों (Prefectures) स चून जात हैं।
काउनसलर का कायकाल 6 वय है, जिनम से आर्थ प्रति 3 वय परचात चूने जात हैं।
अत काउनसलर सदन एक स्थायी सदन है।

जापानी डाइट विधि निर्माण का सर्वोच्च अय है। सविधान के अनुसार वर्ष म डाइट का एक सामाप्य अधिवेदान होना आवश्यक है, लेकिन मित्रमण्डन विद्यय अधिवदान भी आहूत कर सकता है। दोना सदना की कुल सदस्य सक्या क चौबाई या अधिक सदस्या द्वारा अधिवदान बुलाये जान की माँग करने पर अनिवायत अधिवदान

आहुत किया जाता है।

विषेयका का दोनो सदना द्वारा पारित होना आवश्यक होता है। सिक्त वित्त विषेयको को सवप्रयम प्रतिनिधि सदन म ही प्रस्तुत किया जाता है। यदि प्रस्तुत किया जाता है। यदि प्रस्तुत किया जाता के 30 दिन के मीतर काउ सलरो द्वारा वित्त विषेयक पारित नहीं किया जाता अथवा अस्वीकार कर दिया जाता है तो प्रतिनिध सदन उसे वो तिहाई बहुमत से पुन पारित कर सकता है और ऐसी स्थित में बहु रोना सदना द्वारा पारित माना जाता है। यदि गर मिलीय विधेयको को काउ सतर सदक सस्वोक्त कर देता है तो उह भी प्रतिनिध सदम य देता है तो उह भी प्रतिनिध सदम म सदम अप्तिनिध सदम म सदम म स्वीधत विधेयक दोना सदनो द्वारा परित हुआ माना जाता है। दोना सदना म मतभेद हो जान की दशा में दोना सदनो है समुष्क अधिवेशन का विधान है।

मित्रमण्डल के सदस्य विजयक पर विचार विसद्य के समय होनों म से किसी मी सदन मे उपस्थित हो सकते है, चाहे वे उस सदन के सदस्य हा अथवा न हो। मित्रमण्डल सिद्धा तत डाइट के प्रति उत्तरदायी है विकिन व्यवहार म प्रतिनिधि सदन म अविवशस का प्रत्साव पारित होने पर मित्रमण्डल का पतन हो जाता है। बाइट सारियों का अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। यदि द्वितीय सदन किसी सिंप को अनुमोदित नहीं करता और विच विषयक की मौति प्रतिनिधि सदन उसे दो-तिहाई बहुमस से पुन स्वीकृत कर देता है तो ऐसी दशा म उसे सम्मूण डाइट द्वारा

अनुमोदित माना जाता है। स्पष्ट है कि काउ सलर सदन की स्थिति प्रतिनिधि सदन को तलना म हेय है।

जापानी डाइट द्वारा निर्मित विधियाँ सविधान विराधी होने पर सर्वोच्च यायान्तय द्वारा अवैशानित घोषित की जा सनती हैं। जापानी सर्वोच्च यायान्त्रय की सित्तवी अमेरिकी सर्वोच्च नामान्त्रय स्थानित है। हाइट को देश के वित्त पर पूरा नियान्त्रण प्राप्त है। मिं प्रमुख्त के कार्यों पर उसका पूण नियन्त्रण है। प्रधानमान्त्री पर नामान्त्र सम्राट न द्वारा नहीं रिया जाता वरन् डाइट करती है। बाइट को प्रधानमान्त्री पर नामान्त्र मागों को जोच करने एव यायाधीशा पर महामियोग लगाने का अधिकार है। इसने निष्य बाना सदना के समान सदस्यों को मिलाकर एक महामियोग यामालय है। इसने निष्य बाना सदना के समान सदस्यों को मिलाकर एक महामियोग यामालय ही स्थापना की जाती है। अत जापानी डाइट म केवल विधि निर्माण की धी धिस्त्रिय निहंत नहीं है लेकिन यह प्रिटिश ससद की मौति सन्त्रभू नहीं है यद्यपि सविधान के अनुसार विधि निमाण का मर्वाच्च अन है।

नेपाल110 की व्यवस्थापिका---राष्ट्रीय पचायत

नेपाल में एकसदनीय व्यवस्थापिका है। इस राष्ट्रीय पचायत कहत हैं। नेपाल म विकेट्रित पचायती व्यवस्था ना श्रीगणेश किया गया ह।

¹¹⁰ नेपाल भारत के उत्तरी सीमात पर स्थित पहाडी देश है। इसकी अधिकाश जनना हिंदू धर्मावलम्बी है। नेपाल के आधुनिक इतिहास का प्रारम्भ 1768 ई से होता है। नेपाल म दिल्ली समफ्रीता के समय वक राणाओं का धासन या। राणा-परिवार का ज्येष्ठ सदस्य देश का प्रधानमंत्री हुआ करता था एव निरकुरा सत्ता का प्रयोग करताथा। सम्राट उसके होया में करपुततीकी मौति था। साकतन्त्र स्थापित नरने के लिए कुछ प्रयत्न किये गयेथे परतु वे असफल रहे। 1950 ई म नेपाली कांग्रेम द्वारा रामाशाही के निरकुशत न के विरुद्ध महाराज त्रिमुवन बीर विक्रमशाह के सहयोग से विद्रोह किया था। मारत मर्न कार वे महयोग क फतस्वरूप दिल्ली सममीता हुआ और राणाशाही का अंत हुआ। नेपान नरेश पून पदारूढ हुए, लाकतन्त्रीय आदशौं के अनुरूप शासन-ध्यवस्या एव सर्विधान निर्माण हेत् सविधान समा की स्थापना की गयी तथा अत-रिम शासन की स्थापना की गयी। नवीन सविधान के प्रारूप के निर्माण हेत् सर आइवर जेनिनस के निरीक्षण म एक समिति की स्थापना हुई। इसके द्वारा निमित मविधान की 12 फरवरी, 1959 ई को घोषणा की गयी। इसका स्वरूप सस-दीय या, ससद द्विसदना मक थी, निम्न सदन सावजनिक मताधिकार पर निर्मित सदत या तथा मछाट को अविधाष्ट राक्तियाँ प्रदान की गयी यी। यह मविधान 30 जून 1959 ई को क्रियोवित किया गया लेकिन सफलतापूरक चल नही 30 जून 1922 २ १००० ई म नेपाल नरेश न सविधान मन कर १९५१ है। सका । दिसम्बर 1960 ई म नेपाल नरेश न सविधान की असफलता का मुख्य कारण असति सूत्र अपने हाथा में ने लिया । इस मविधान की असफलता का मुख्य कारण की उन्हें परम्पराएँ नहीं भी और तथा राजनीतिक दलो म आवश्यक चेतना का अमाव या तथा जनता

सगठन—प्रामा स लेकर राष्ट्रीय स्वर तक पिरामिडाकार हुए म प्वायता की स्थापना को गयी है। नेपाली राष्ट्रीय प्वायत की सदस्य-सम्या 125 निपास्ति की गयी है। यह अय लोकत त्रीय दक्षा के निम्म सदना की मीति सावजिक सताधिकार पर आधारित लोकप्रिय सदन नहीं है चरन् इसके 90 सदस्य जवस समाओ, 16 वर्गीय एव व्यायसाधिक सगठना तथा 4 स्नातका द्वारा निर्वाचित किय जाते हैं और 16 सदस्या को सम्राट मनानीत करता है। अत यह निवाचित एव मनोनीत सदन है। विभिन्न अंशी क सदस्या के कायकाल भी पृषक पृथक हैं। अचत समाओ द्वारा निवाचित सदस्या का कायकाल 6 वय है, इसके एक तिहाई सदस्य प्रति दो वय परवात अवकाश प्रहण कर लेत हैं। वेच समी श्रंपी क सदना का कायकाल वार वय है। राष्ट्रीय प्रवायत की एक 21 सदस्यी निर्देशक समिति है।

राष्ट्रीय प्रचायत की सदस्यता सम्य भी योग्यताएँ निम्नसिक्षित हैं—(1) नेपासी नागरिक होना चाहिए, (2) कम से कम 25 वप की आयु हो, (3) धासत्रीय सेवा में नहीं होना चाहिए, लेकिन मात्री एवं सहायक मात्री इस नियम संमुक्त हैं, (4) गोप नीयता मग करने का अपराधी नहीं होना चाहिए, और (5) किसी विधि क अतगत

अयोग्य न ठहराया गया हो।

सम्राट राष्ट्रीय पचायत के किसी सदस्य का गोपनीयता मन करन के आराप में आयोग द्वारा पदच्युत करने की सिफारिश करने पर उस पदच्युत कर सकता है। राष्ट्रीय पचायत का अध्यक्ष, सर्वोच्च यायात्तव का यायाधीश तथा राज्यसमा का एक

सदस्य इस आयोग के सदस्य होते है।

अस्पक्ष—राट्रीय प्रवादत का एक अध्यक्ष होता है जो प्रवादत की विकारित पर प्रवादत का एक अध्यक्ष होता है जो प्रवादत की विकारित पर प्रवादत होंगे कि किया जाता है। इसका कायकाल 2 वप है। वह पुर्तिकों बित हो सकता है। राष्ट्रीय प्रवादत के कुत सदस्या के वो तिहाई सदस्या के बेहुमर्त की विकारित पर सम्राट अध्यक्ष को पदच्युत कर सकता है। अध्यक्ष पर का रिक्त होने या बीमारी या अया कारण से अपने वाधिस्वों का सम्पादन कर सकता एक स्वाद के अपने वाधिस्वों का सम्पादन कर सकता एक स्वाद के अधिस पर उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्यों को सम्पादित करता है।

और राजनीतिक वातावरण अप्टवा। वेपास का वतपान सिवधान 1962 ई म लागू किया गया जो एक समिति के सहयोग से बनाया गया था। इसकी मुख्य विश्वपताएँ निम्न हैं—(1) यह सिखित, निर्मित एक कठोर सिवधान है (2) सम्राट द्वारा प्रवत्त है सम्बन्धना सम्राट य निहित है। सम्राट सम्पूण पाजनीतिक व्यवस्था की कद्रीय धुरी है, (3) नेपाल एक स्वत व, अविमाज्य एव सावमीम राजत नीय हिंदू राज्य है, (4) विकेडित लोकत न के आधार पर पवायती व्यवस्था की स्थापना की मयी है (5) मीतिक अविकारों गत सावयत्तिक सीति के उद्देश्यों एक सिद्धा ता का सविधान म उल्लेख है, (6) एकारमक राज्य एव (7) सबरीय तथा पन्यस्थातम्ब सीवल-पद्धतिया का मिश्रण है। नेपाती सविधान देश की मीतिक विषि (fundamental law) है।

व्यवस्थापिका—प्रथम या निम्न सदन | 349 राष्ट्रीय पचायत का अध्यक्ष उत्तव अधिवसना की अध्यक्षता करता है, पचायत क अधिवसना म जनुतासन रखता है, सदन का नायश्रम निर्धारित करता है एव विनिम्न नायत्रमा ना समय निश्चित करता ह तथा राष्ट्रीय पंचायत वे नियमा का पालन बराता है। एक प्रवार स वह सम्राट एवं राष्ट्रीय पंचायत के मध्य कडी का नाय करता है। वह किसी भी सदस्य का अनुसासन मम करन पर दण्ड दे सकता है। उस निद्धासित एवं सदस्यता से निविच्यत कर सनता है, सदस्या की मापण एवं वाद-विवाद को अनुमति प्रदान बरता है विवाद की स्थिति म निर्णायक मत देता है। वैस सामा यत यह मन नहीं दता है। जच्यक्ष की स्विति जय देवी के विधानमण्डला के अध्यक्षा की ही मीति है।

राष्ट्रीय पचायत अपन सदस्या म स एक को उपाध्यक्ष चूनती है जो अध्यक्ष को अनुपस्थिति म राष्टीय पचापत के अधिवेदानों की अध्यक्षता करता है।

सन्न — सन्नाट को प्रचायत के अधिवरान को श्राहत करने का अधिकार प्राप्त है लेक्नि प्रथम एव दितीय अधिवेदान के मध्य 6 माह स अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए । सम्राट को राष्ट्रीय प्रवासत का अधिवसन निश्चित विधि के पूर्व आहुत करत का अधिकार है। प्रथम सर्वेद्यानिक सत्तीयन (1967 है) के पूर्व राष्ट्रीय पद्मा-यत के खुले अधिवदान नहीं होते थ । सभी अधिवेशन बद कसरे म हुआ करत थे । वितिन अब सम्मालन म कुछ श्रेणिया की प्रचायतो एव वर्गीय संगठनो के प्रतिनिधया को उपस्थित होने की अनुमति है। सम्राट को प्रेस एव बनता के लिए भी अधिनेशन खुला घोषित करने का अधिकार है। सम्राट को राष्ट्रीय पंचायत के अधिवेशन म मापण दन का अधिकार है तथा वह राष्ट्रीय पचायत को सदश भी भेज सकता है। राष्ट्रीय पनायत के सदस्या को बहुमत से सम्राट के पास स देश भेजने का अधिकार है।

कुल सदस्य-सहया के एक विहाई सदस्या की उपस्थिति येणपूर्ति के लिए अनिवाय है।

विधायी काय-वह दस का एक मान विधानमण्डल है। विधि निर्माण जसका प्रमुख काय है। राष्ट्रीय पनायत क विधेयक सम्राट की स्वीकृति के पश्चात ही विधि बनते हैं। वित्त, सबा एवं मौतिक अधिकार सम्ब भी विधेयन सम्राट की पूर्व-स्वीकृति ते ही राष्ट्रीय प्रवासत म उपस्थित किय जा सकते हैं। सम्राट की अध्यादेश जारी करने का अधिकार है लेकिन ऐसे अध्यादेशा की राष्ट्रीय पनायत के आगामी सन म प्रथम अधिवेदान के सात दिन के अंदर उपस्थित करना आवत्यक है। यदि अध्यादेता को प्रचावत स्वीकृत नहीं करती है तो वे तुरत समान्त हो जात हैं। यदि वे प्रचायत के सत्र म स्वोक्वति हतु उपस्यित नहीं किय बाते वी राष्ट्रीय प्वायत के विषिवेश्वन के 40 दिना क परवात स्वत ही समाप्त हो बात है।

कायपालिका सम्ब धो काय —मिनमण्डल के सदस्य राष्ट्रीय पद्मायत के

सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय पचायत के सदस्या को उनके कार्यों की आलोचना ना अधि कार है। वे प्रस्त, पूरक प्रस्त वृद्ध सकते हैं एवं वाद विवाद की माँग कर सकते हैं। राष्ट्रीय पचायत अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर सकती है। निसी मंत्री के विरुद्ध राष्ट्रीय पचायत के सदस्य अपन 2/3 बहुमत से अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। किमन सम्राट ऐसे प्रस्तावा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने क लिए स्वतंत्र है। स्मरणीय है कि मित्रिय पचायत के प्रति उत्तरदायीन होकर सम्राट के प्रति उत्तरदायीन होकर सम्राट के प्रति उत्तरदायी होता है।

यापिक काय--राष्टीय पंचायत को सर्वोच्च यायालय के किसी यायापीय की अक्षमता या कदाचार के कारण असमय होने पर उस पदच्युत करते हेतु सम्राट की सम्बोधित करने का अधिकार है।

वित्तीय काय---वापिक वजट पारित करना और कर निघारण राष्टीय पदा यत द्वारा ही किय जाते हैं। सचित निधि पर मारित व्यया को राष्ट्रीय पदायत पारित नहीं करती है अपित उन पर केवल सदन म बाद-विवाद होता है।

अप काय—राष्ट्रीय पचायत अपने बच्चक्ष एव समितियो के सहस्यों का निर्वाचन करती है। सर्वेचानिक संशोधन के हेतु निर्मित विशिष्ट समिति में राष्टीय पचायत की स्थायी समिति के सदस्य होते हैं।

मुखाकन

राप्टीय पंचायत विधायी सदन है। लेकिन इसका गठन एवं एक्तिया लोकत त्रीय सिद्धा तो पर अपेक्षाकृत कम ही आधारित हैं। यह अप्रत्यक्ष रीति स निवर्णित सबस है। मिनमण्डल (कायपालिला) इसके प्रति उत्तरदायी नहीं है। राष्ट्रीय समा के सदस्य सदन के दो-तिहाई बहुमत से मंत्री का परच्युत करने की केवल मान कर सकते हैं, इस मांग को स्वीकार या अव्यक्तिक करना सवाद की इच्छा पर निमर है। सवैधानिक सवीधन के स्वस्य में इसे कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। यह सविधान के यायाधीशा को पदच्युत करने की केवल सिफारिश कर सकती है। यह मानमण्डल पर केवल प्रवत पूछ कर तिय त्रण एवं सकती है। तिकृत इस प्रकार का निय त्रण व्यवहार य निष्प्रयावी है क्योंकि मान्यमण्डल सम्राट के प्रति उत्तरदायी होता है। इसकी स्थिति व्रिटिश सवद एवं मारतीय सवस की तुलना मनण्य है। यह वहुत कुछ स्वत जता से पूज की 'भारतीय कंद्रीय धारासमा' के समक्ष है। नेपाल म दलीय व्यवस्य का जमाव है। फतस्वस्थ राष्ट्रीय पंचायत स्वर यह स्वर प्याप्त स्वर राष्ट्रीय पंचायत के सदस्य व्यक्तिगत रूप में ही अपने विचार व्यवस्य है। राजनीतिक दना को 1962 ई म समारत करके उनके स्थान पर 5 वर्षीय स्वरत्नीः का निर्माण किया गया है।

¹¹¹ ये वर्गीय सगठन इस प्रकार है (1) नेपाल कृपक सगठन, (2) नेपाल प्रवण सगठन, (3) नेपाल नारी सगठन (4) नेपाल श्रमिक सगठन, एव (5) नेपाल भूतपुर्व सनिक सगठन ।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पंचायत म बुछ मनोनीत सदस्य होते हैं । अंत ऐसे सदन से व्यवस्यापिका—प्रथम या निम्न सदन | 351 .57 यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह राज्यसत्ता का केंद्र वन सकेगा । नेपाल म ₽,1 राष्ट्रीय पनायत की स्थिति सम्राट की तुलना म गोण है। श्रीम नारायण अपवाल के 41 अनुवार नेपाल नरेश दल-विहीन पदायवी लोकत न की इस प्रणाली की स्यापना के -निए कृत सकत्य हैं। उनके इस प्रयत्न क विरुद्ध सचेह व्यक्त किये जाते रहे हैं एव प्रत्यक्ष एवं अत्रत्यक्ष रूप मं समदीय लोकतंत्रीय व्यवस्था की स्थापना की माँग उठती रही है। नेपाली काग्रस के नेता वो भी कोइराला इस मत के मुख्य समयक है। नेपात नरेश की हिन्दि म राजनीतिक हलो की पुनस्पापना नेपाल जैसे देश म कल्याण-कारी राज्य की स्थापना की होटि से उचित नहीं हैं। नेपानी पचायती व्यवस्था में ग्राम्य कारा राज्य का रचामा का डाल्च व जाप एए हुए सामा है । जारा चारा व वास्त पर वयस्क मताधिकार वर प्रत्यक्ष प्रजात य की स्थापना की गयी है। जिला क्षेत्र, एव राष्ट्रीय स्तर के उच्च निकायअप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। श्रीमनारायण अप्र-वाल के अनुसार, 'में छाटे एव विकासो मुख देश नेवाल म इस प्रकारके प्रवात नमें कोई हानि नहीं देखता । गांधींको ने स्वतं निम्नतम् स्वरां पर प्रत्यक्ष तोकतं व एव शीपस्य राण १० विष्य अप्रत्यक्ष निर्वाचन का सुकाव दिया है। नेपाल की इस लोकतानीय व्यवस्था का मुख्य दोष एव कमी यह है कि राष्ट्रीय पचायत की प्रथानमंत्री के रूप में काम करने हेतु अपना नेता चुनने की अनुमति प्राप्त नहीं है। वतमान व्यवस्था के त्र काथ करते रहे जाता. त्या के वास्त्र के प्रतासक्ष के प्रसास के प्रसास के प्रसास के प्रसास के प्रसास के प्रसास म ती की नियुक्ति कर सकते हैं। 128

1962 ई के पान सिवधान के अ तगत पाकिस्तान विधानमण्डल एकसदनीय था। इसको राष्ट्रीय समा (National Assembly) की सन्ना दी गयी थी एव इसकी सदस्य रवामा राष्ट्राय वामा । विभागता । स्वतिमानिक संदोधन द्वारा इसकी संदर्शनसरमा वदाकर 218 कर दी गयी थी। राष्ट्रीय समा म 6 स्थान स्त्रिया के लिए सुरक्षित किये गये थे तया पूर्वी एव पश्चिमी पाक हे बरावर सस्या ने सदस्य निवाचित होते थे। 1967 ई तथा तथा प्रभाव है। प्रभाव क्षेत्र विद्यान क्षेत्र विद्यान क्षेत्र विद्यानमञ्जलों के अध्यक्षी, प्रत्याचाम् वर्षाम् अस्त्रः अस त्रिक्षाता, मन्त्रियो एव कता, विचान या चाहित्य के क्षेत्र य स्वातिनामा विद्वाना क निए पुरक्षित किये गये वे जिस 1970 ई से क्रिया वित किया जाना था। राष्ट्रीय समा का कायकाल 5 वप या वेकिन इसे इस अवधि से पूत्र भी विष्टित किया वा सकता या और अपन कायकाल की समाचि वर सदम स्वत् विषटित हो जाता था। राष्ट्रीय समा को आहुँए करने एवं उसके संवायसान तथा स्थिति एवं विषटित करने के अधि-तथा का जाहुस करन एक जनम्यात जना स्वास्त एक जनमन्त कर के साथ है। साहीस समा है सबसा की एक-तिहाई सदस्यों होस कार राष्ट्रपत का आप्त वा चान्द्राच चना क जन्मच का द्वानाव्यव चन्त्रा का अधिकार या लेकिन राष्ट्रपति इस स्थमित 112 S Naram India and Nepal, pp 89 90

352 | आधुनिक शासनतात्र

रिक्त होने पर सर्वोच्च यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रीय समा को जाहूत करने का अधिकार था। राष्ट्रपति राष्ट्रीय समा को विषटित कर सकता या लेकिन विषटत की तिथि से तीन माह के अदर निर्वाचन का होना आवश्यक था। राष्ट्रीय समा ना निर्वाचन निर्वाचन निर्वाचन निर्वाचन मण्डल के सदस्यो द्वारा किया जाता था। 1155 प्रति 6 माह म इसना एक अधिवेशन होना अनिवाय था। इसका अध्यक्ष राष्ट्रीय सभा के सदस्या द्वारा जुना जाता था। राष्ट्रपति के पदच्युत होने तथा उसकी कारीरिक या मानसिक अन्वस्कता की दशा म राष्ट्रीय सभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति के एन म काय कर सकता था। विधान मण्डल के अध्यक्षो के परम्परागत कृत्य अध्यक्ष द्वारा सम्पादित किय जाते थे।

113 15 अगस्त, 1947 ई को मारत विमाजन के साथ पाकिस्तान का जम हुआ है । इस प्रदेश का उदय मुस्लिम साम्प्रदायिकता एव द्विराष्ट्र सिद्धा त का परिणाम है। 1961 ई म इसकी जनसरया 9 के करोड थी। यह मुस्लिम वहुल देश है। ज म के समय पाकिस्तान के दो माग थे—पूर्वी पाकिस्तान जो अब बगला देश के रूप म सम्पूण-प्रमुख सम्यान राष्ट्र वन चुका है, एव पश्चिमी पाकिस्तान। पाकि स्तान इस्लामी राज्य है। पाकिस्तान म व्यक्तियत एव सामाजिक जीवन के प्रस्पक पहलू पर इस्लाम छाया हुआ है। पाकिस्तान का प्रथम सविधान 1956 में बना या । 1947 मा 1956 ई तक पाविस्तान का शासन भारतीय शासन अधिनियम, 1935 ई के अनुसार समठित किया गया या एव उसके अनुसार चलता रहा। इसम् आवश्यकतानुसार समय समय पर परिवतन कर दियं गयं थे। पाकिस्तान के निर्माता श्री मोहम्मद अली जिना 1947 ई मे ही प्रथम गवनर जनरल नियुक्त किये गयेथे। 1947 ई म गठित पाक सविवान समा मारत शासन अधिनियम 1935 ई के अनुसार सपीय व्यवस्थापिका के रूप म काय करती रही । इसके अतिरिक्त एक संघीय यायालय (Federal Court) भी था। सर्वि धान समा ने 19>6 ई मे सविधान-निर्माण का काय पूरा किया और 23 माच, 1956 को नवीन सविधान लागू किया गया । 1956 इ के पाक के इस्लामी गणराज्य की मुख्य विशेषताएँ निम्नवत हैं (1) इस्लाम के सामाजिक याय क सिद्धाता पर पाक राज्य कानिर्माण किया गया था। (2) सिवधान म नीति निर्देशक तत्वा की व्यवस्था की गयी थी। (3) वित्त-आयोग एव राष्ट्रीय वित्त समिति की स्यापना की गयी थी। (4) सच गणराज्य की स्थापना की गयी एव अविशिष्ट शक्तियी प्रा तो का प्रदान की गयी। (5) गवनर-जनरल के स्थानपर निर्वाचित राष्ट्रपतिका विषान किया गया । (6) के द्र एव प्रा ता म एकसदनीय विघानमण्डला की स्थापना की गयी। (7) ससदीय द्वासन-व्यवस्था की स्थापना की गयी थी तथा पार्क राप्ट्रपति के लिए मित्रया के परामद्य पर काय करना आवश्यक था। (8) सर्वोच्च यायालय एव उच्च न्यायालयां की स्थापना की गयी थी। यायपालिका सविधान नो सरक्षक यो एव उसे व्याख्या ना अधिकार प्राप्तथा। (9) सविधान म मौतिक अधिनारा ना उल्लख निया गया था। (10) एनल नागरिकता ना निर्माण किया गया । (11) सविधान कठार नही था । कुछ अस्यायी अनुच्छे । व निर्माण द्वारा मियपान में संनापन निया जा सनता था जो मसद द्वारा निरस्त न निय जाने तक प्रमाबी हाते थ ।

राष्ट्रीय समा का मुरय काय विधि निर्माणकरना या और सर्विधान द्वारा उल्लि व्यवस्थापिका—प्रथम या निम्न सदन | 353 सित विधि निर्माण के सिद्धा ता का उसके द्वारा पालन आवस्यक था। यायालया को इन सिद्धा ता के विषयीत विषियों को अवैधानिक घोषित करने का अधिकार दिया गया या । विधिया के पारित होने के 30 दिन के भीतर उन्हें स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार दिवा गया था। राष्ट्रीय समा अस्बोक्त विधेयका को पुन अपने दो तिहाई का बावकार एक्वा गया था। सम्झय वया जरबाद्या एक्वयमा गा उन जनम वा ग्रहार बहुमत से पारित कर सकती थी। ऐसी अवस्या म राष्ट्रपति के सिए 10 दिन के मौतर बहुमत संभारत कर कण्वा था। एवा ज्यस्या म अपूराल मान्यस्था मान्यस्य उर्ग भारत वा या विधेयक को जनमत संबह के लिए निर्वाचकाणां को भेज सकता था।

यह सिवधान सफलतापुवक न चल सका। 7 अवद्वर, 1958 ई को कोटड मासल मोहम्मद वयुव खाँ ने चैनिक धासन को घोषणा कर दी एव पाक फाल्ड मार्शन माह्नम्मद बञ्चव वा ग सामक श्रासम का पापपा कर वा एव पाक राजनीति की सफाई का प्रयत्न किया 117 फरवरी, 1960 के को अयुव खा हारा वाहिस्तान में बसदीय शासन की असफतता तथा नवीन संविधान की क्य हारा आकरणात्र स चावतत आयात्र का लगणावा छन्। त्यां माववात का रूप रेका प्रस्तुत करते के लिए एक बायोग की स्थापना की यथी। इस बायोग के ९का अच्छत करन का छार एक जावान का च्यापना का प्या । इस आयाग क प्रतिवदन पर पाक के दितीय नवीन सर्विधान का निर्माण किया गया। यह 8 जून,

अपूत्रसाही के विरुद्ध तोनत त्रीय शक्तियां धीरे धीरे सित्रय होने लगी। हुआ। 190/ ६ म श्रा मुद्धा न लाकत न का स्थापना क लाए पायुस्त पाटा का निर्माण किया। 21 माच, 1969 ई को राष्ट्रपति जनस्त अपूर्व ने पाक का गमाण कथा । ८६ नाच, ४२००२ ३ का सम्प्रमात भगरण अपूर न पाक वेनापति जनरत याहिया चा को पाक्तितान को मुख्य सनिक प्रशासक नियुक्त क्षांता जनरू वात्वा का का भार त्यान का उप्त वानक स्थातक निर्धात का उपात किया। जनक बारा 1962 रेका चावचात रह कर विचा वया। जा मान, 1969 ई को वे राष्ट्रपति बने एवं 4 अप्रत को उहीने 1962 र्डक संविधान के 1909 इ का व राष्ट्रपात वन एव क अभव का व हान 1902 इ क सावधान क इंड उपन घा को लागू किया तथा एक नवीन सनिधान क निर्माण की धोषणा की । हुँध उपने था का लागू किया जमा एक ग्वाम वावधान का गवाल का वावधान की व्यक्त भवाधिकार के जाधार पर राष्ट्रीय समा के चुनाव अवद्भर 1210 का प्रभाव नवास्त्रकार के वाबार पर उप्टाब तथा क प्रगाव हुए रातु नवीन राष्ट्रीय समा 120 दिन में संविधान न बना सकी । फलस्वस्त्र हुए पर ज तथान राष्ट्रांव छन। १८० १६न न छापवान म वमा छन। । कारावस्य नवीन निर्वाचन किस मुखे । वृत्तें पाकिस्तान म सुवीबुरहमान के नेतरन म अवामी नवान । नवाचन । क्रम नव । द्वा भाक्ताता च दुबादु प्रभाव के कार्य च जावान तीम ने इन निर्वाचमा से 169 म ते 167 स्थान प्राप्त किये। श्री मुझे की पीपुत्स तीम में इन निवाधना में 100 में से 107 स्थान आग्वाफ्य । आ ग्रेटी का पाउटा पार्टी को 83 स्पान मिले । अय देता को तीप 61 स्पान प्राप्त हुए से। मुट्टी एव पाटा का 00 रमाम मध्य । अब क्या का चप एउ स्थान आस्त हुए व । मुद्दा एव याहिया को मुजीब की नीति एस द नहीं थी खत राष्ट्रीय समा को बठक स्विति याहिम का युगाव का नाात पस द नहां था जव राष्ट्राय सभा का बठक स्थापत कर दी गयी। फतस्वरूप राजनीतिक गतिरोम जस न हो गया। यूर्वी पाक म पाक कर वा ११४१। १ कारवरू पंजनातक गांव धव जरा न हो १४४। । अंश पंजनातक न वा अधिकारियों के अधिकारियों ने जहाँ स्वतंत्र के स्वतंत्र श्रीभन्तारमा क करवाचारा न च हे स्वत नता क स्वरं वध्य करन का वास्य कर १०२१ है एवं समय के एस्सात बेसेना देस का जम हेवा। दिया। संग्रहन । वहाहुं एवं संप्रप क पश्चीत संगता ६ व भा न हुआ । 20 दिसन्दर, 1971 ई नो प्राक्त की परान्य ने पश्चीत महो राष्ट्रपति वन । १९९९ ६ के किया के स्वाहत महो राष्ट्रपति वने । वर्ष (क्षाचर) १२११ र ११ भक्त भाग का उर्धावर र १९४१० वृद्धा (क्ष्ट्रभव का 1 1962 ई के तिविधान को समान्त कर दिया गया । 1972 ई में संतीय नवीर 1302 व क वादवान का क्यान्त कर दिवा ग्या । 1312 व म ववाय नवान विद्यान बना । दुवी पाक को स्वत व होने के प्रश्वात पाकिस्तान में पुन संस्तेत वावधान पता । त्रुवा भाक का त्यव व होन क प्रवाद पाकित्वान मुन् संसदाय वीतिन की स्थापना की गयी है । सैनियान के अनुसार पाकित्वान मुन् संसदाय को कि कि का का के अभिन्त अस्तिक के अनुसार पाकित्वान के ग्रामाराज्य पायत का स्वापना का प्रवाह है। वाववान क व्यवधार पानस्वान कार मीपित किया गया है। मीलिक विकासे की भी व्यवस्था की गयी है।

354 | जाधुनिक शासनतात्र

इस प्रयोग का असफल होना स्वामाविक था।

जनमत संग्रह म दा तिहाई प्रहुमत से समयन प्राप्त होने पर विशेषक पारित हो जाता या । राष्ट्रीय समा की नित्तीय सक्तियाँ नगण्य थी । उसमे केवल वजट के अनुदाना पर ही मतदान हाता था यद्यपि सदस्यो को सम्पूण वजट पर बहम का अधिकार प्राप्त था। भाग व्यय की किसी राशि का राष्ट्रीय समा द्वारा अनुमोदन न किये जाने पर शासन का पदन्या की आवश्यकता नहीं थी। सदस्या को बाद विवाद की सुविधा प्राप्त थी। वे प्रक्त एव पूरक प्रक्त पूछ सकते थे परातु मानी जनका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं थे। मूल्याकन-पाक राष्ट्रीय समा जनमन की नापने का उपयुक्त यात नहीं थी। यह अप्रत्यक्ष रीति स निवाचित सदन था । निर्वाचक मण्डल के सदस्यगण पाक की जनता का विकत्प नहीं हा मकते थे। निर्वाचन की जिस अवस्यक्ष व्यवस्था को अपूर खा ने चाल किया था उसका मुख्य उद्देश्य दतीय व्यवस्या के दीयों की दूर करना था । लेकिन यह उद्देश्य भी पूर्ण नहीं हुआा राष्ट्रीय समा विश्वादी एवं वाद विवादकरने वाले सदन के रूप में भी ठीक दग से नाय न कर सकी। उसकी शक्ति सीमित थी। गप्द पति को कुछ विधायी अधिकार प्राप्त थे। इसके अतिरिक्त उसे समा का विषटित करने की शक्ति भी प्राप्त थी । इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति का व्यापक आपातनातीन विधायी वाक्तिया प्राप्त थी । राष्ट्रीय ममा की विनीय बक्ति नाममात्र की थी । सरकार पर उसका कोई नियानण नहीं था अपितु राष्ट्रीय सना पर शासन का ही नियाण रहता या । राप्टीय समा म सरकार की पराजय का अब झासन द्वारा प्रत्याग करना नही हुआ करता था। इस सविधान क अधीन पाक म तक्सदनीय व्यवस्थापिका का अनाला प्रयोग किया गया था । स्मरणीय है कि पाक जैस वडे देशो म जहाँ भाषा एव क्षेत्र की विभिन्तताएँ पायी जाती हा एवं सधीय शासन के लिए जो उवर भूमि हो, वहाँ

12

व्यवस्थापिका—विधि-निर्माण प्रिक्रया एव सम्बन्धित विपय [LEGISLATURES—LAW MAKING AND THE RELATED SUBJECTS]

इस अध्याय मे व्यवस्थापिका के प्रमुख दायित्व विधि निर्माण की प्रतिया एव जससे सम्बन्धित विषयो जैस व्यवस्थापिका के अध्यक्ष एव जनके अधिकारो सम्बाधी प्रश्नो का अध्ययन किया गया है। विधि निर्माण की भी विभिन्न देशा म पुथक पुथक प्रणालिया है। वित्त विधेयक एव गैर वित्तीय विधेयक को पारित करने क लिए मिन पद्धतिया का प्रयोग किया जाता है। आज मी स्विट्जरलैण्ड के कूछ केण्टता एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्यों म प्रत्यक्ष रीति संविधि निर्माण होता है। हर देश में विधि निर्माण में व्यवस्थापिका की समितिया महत्वपूर्ण योग देती है। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन व जमेरिकाकी समिति व्यवस्था मं अत्तर ह । व्यवस्थापिका विधि निमाण सम्बाधी सभी दायित्वा को अनेक कारणी संस्वय पूरा नहीं कर पाती है। कार्याधिक्य एव समयाभाव तथा तक्तीकी विषया सम्बन्धी अपेक्षित ज्ञान का अभाव इसका प्रधान कारण है। अत व्यवस्थापिका विधि से सम्बन्धित सामा य सिद्धातों को निधारित करके तत्सम्बंधी नियमा एवं उपनियमा के निर्माण का दायित्व कायपालिका को सौप देती है। इस व्यवस्था को प्रदत्त विधान (Delegated Legislation) कहते है । इस अध्याय में व्यवस्थापिका के अध्यक्ष, विभिन्न विधि निमाण पद्धतिया, एवं समिति व्यवस्था का उल्लेख किया गया है तथा अगले अध्याया म प्रत्यक्ष विधि निर्माण , प्रदत्त व्यवस्थापन एव सदस्यो क विशेषाविकार सम्ब वी प्रश्नो का अध्ययन किया गया है।

> व्यवस्थापिका के अध्यक्ष विधि निमाण व्यवस्थापिका का प्रधान काय है। बाद विदाद एव विचार-

विमर्श विधि निर्माण के आवत्यक एव अनिवास तत्व हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यवस्था पिका की अपनी काय-पद्धित या काम सचालन रीति और उसी से सम्बंधित नियम भी होते है । उन नियमों का किया वयन व्यवस्थापिका के बहमस्यक सदस्या एव समाज की यांग एव विवक की घारणा तथा विधानमण्डल द्वारा विचाराधीन एवं सम्पा दिन क्ये जाने वाल काय की प्रकृति सम्बन्धी ज्ञान पर निमर करता है। व्यवस्थापिका की प्रतिष्ठा उसके निणया पर निमर करती है । व्यवस्थापिका के काय सवातन सम्ब वी नियमों को मली-माति किया वित करने के लिए एक अधिकारी की आव श्यकता है जा उनकी व्याग्या कर सबे एव उन्ह व्यवहार में जा सके। अत फाइनर र अनुसार विवासमण्डल के "अप्यक्ष (Presiding Officer) में अनेक गुण होते चाहिए विचार अभिव्यक्ति के समय नियुणता या चतुराई (tact) के साय-साय उसे पदाप्तत सजग हाना चाहिए जिससे कि नुदियों को पकडकर अध्यवस्या को रोका ना सके । उसक प्रमुख गुण उसकी निषय-शक्ति एव निष्पक्षता है एव (अध्यक्ष के लिए) नियमों क ज्ञान की आवज्यकता सुस्पन्ट ही है। " निष्पक्षता के लिए किसी सप्ट प्रमाण की जाव पकता नहीं होती है। फैच राष्ट्रीय सभा (French Nanonal Assembly) एव सयुनत राज्य अमेरिका ने प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष निष्पक्ष नहीं होत । अध्यक्ष के पक्षवालपुण हरिटकोण एव व्यवहार सं समय का अपन्यय होता है क्यों एसी अवस्था म उसके निणया को प्रति क्षण चुनौती दी जा सकती है। इसका एक अप वुष्पिणाम भी हाता है। विभि निर्माण मे यदि शासन अत्मधिक हस्तक्षेप करता है ता उस पर यह आरोप लगाया जा सकता है कि जी विधियाँ पारित की गयी हैं वे अनुचित उग से पारित की गयी हैं। ऐसी अवस्था म विधिया अपनी पवित्रता एव प्रभाव जो बैठती हैं । इसके अतिरिक्त अध्यक्ष क पक्षपातपूर्ण व्यवहार से ध्यवस्थापिका म अञ्चनस्या की हर सम्मानता रहती है। अन्य व्यवस्थापिकाओं की अपेक्षा ब्रिटिश ससद के अध्यान अपने जाचरण में पूणत निष्पक्ष होने हैं। ससदीय देशा में निम्न सदन के अध्यान की निष्पक्षता एवं निदलीयता लोकतान की सफलता के लिए "याय पानिका की निष्पक्षता एवं ससदीय संत्रभता क समान ही आवश्यक है।

उच्च सदनो के अध्यक्ष

अग्नम पृष्ठा म निष्न सदन के अध्यक्षा (speakers) का विस्तार म अध्यक्त निया गया है। यहाँ यह स्वरणीय है कि उच्च सदनों के मी अध्यक्ष (Presidias Officers) हान हैं। अध्यक्षा क अविरिक्त व्यवस्थापिका के अय अधिकारी की होत

² A Presiding officer needs many qualities for instance tact and sufficient alertness during hours of speeches to detect and stop any disorder. The prime qualities are decinon and impartiality. The need for a knowledge of ruler is obvious "—Finer, H. op. cit., p. 474.

व्यवस्थापिका—विधि निर्माण प्रनिया एव सम्बन्धित निपय | 357 हैं, यथा—व्यवस्यापिका के सचिव एवं उसके अय सहयोगी अधिकारी। व्यवस्थापिका े. का अपना सचिवालय भी होता है।

विदिश ताँडसभा के बध्यक्ष को लाड चा सतर (Lord Chancellor) कहते हैं। वह मित्रमण्डल का सदस्य होता है और मित्रमण्डल के काय काल-पय त लाडसमा का अध्यक्ष रहता है। उसकी नियुक्ति के सदम म सदन सं परामग्र नहीं किया जाता। प्रधानम भी इसक नाम की सिफारिस करता है। मिनमण्डल के सदस्य के रूप म बह लाडसमा का पदेन अध्यक्ष है। काम स समा क स्पीकर की तुलना म लॉडसमा के अध्यक्ष की शक्तिया नगण्य है। उवाहरण के लिए, यदि सो मा अभाग में अध्यक्षण में मानामा मा भागमा भाग है। ज्याद्वरम मान स्वस्य एक साथ बोलने के लिए खडे होते हैं तो यह निणय करना सदन का काय है कि पहले कीन बोलेगा। लॉडसमा म व्यवस्था स्यापित करने का वायित्व अध्यक्ष का नहीं अपितु सदन ही का होता है। सदस्यगण अध्यक्ष को सम्बोधित न करके साथी मा पर नाम प्रमा एक ए एक एक विस्वीचित करते हैं। यदि लॉड वा सलर पीयर है तो वह सदन के बाद विवाद म माग ने सकता है अयम नहीं। बाद विवाद म माग नेते पर प्रवास की कुर्ती से हट जाता है। वह दलीय आधार पर मत भी वे सकता धार वह निर्णायक सत प्राप्त नहीं है। उसकी अनुपस्थिति म नाउन हारा नियुक्त हे जात र जा जिस्ता है। विश्वन जाच्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है।

अमेरिको सोनेड का अध्यक्ष अमेरिकी सच का उपराष्ट्रपति होता है। मकार, मारतीय उच्च तदन (राज्यसमा) की अध्यक्षता भी उपराष्ट्रपति (vice pres dent) करता है। बोनों ही उपराद्रपति अपने-अपने देशों के उच्च सदनों के पदे बच्छा होते हैं। दोना ही अपने कायकाल पय त अपने-अपने सदना की अध्यक्षता वाब्बन होता है। कामें हो अवत् भाषणाच्या ज्यात व्यवस्था करते हैं। जनके अधिकार व शनितया निम्म सदना के अध्यक्षी (स्पीकर) की ही माति होती है। मारत में उपराद्भिति की अनुपस्मिति में सदन की अध्यक्षता क लिए सदन अपने म से ही उपाध्यक्ष का निर्वाचन करता है। उपाध्यक्ष को सदन साधारण वहुमत ते प्रस्ताव पारित करके पदस्युत कर सकता है। भारतीय जगराज्यस्य वासारन का सदस्य मही होता, उसे केवल निर्णायक मत प्राप्त है।

Other permanent officials of the House of Lords are the clerk of Other permanent oricials of the House of Lords are the cierk of the parliament, the Clerk Assistant the Reading Clerk the Fourth the parliament, the Clerk Assistant the Reading Clerk the Fourth Clerk (Judicial) the Gentleman Usher of the Black Rod and Services of the Black Rod and Ser

¹⁹⁷³ P 8

Hot Pp 7 8

Article 1 Section III of the U S

American Government 1967 P 686 also

मिन दल का हो मकता है। सीनेट की समितियों की वह नियुक्ति नहीं करता और वेचल विवाद की स्थिति में ही निणायक मत देना है। सीनेट का अध्यक्ष प्रत्येक सदस्य का उसी कम में विचार व्यक्त करने का अवसर देना है जिस कम म वे खडे हात करे है। अत उसे प्रतिनिधि सदन के स्पीकर की माँति स्वीकृत करने (recognition) नी शक्ति प्राप्त नहीं है। उपराप्त्यति प्रतिनिधि सदन के स्पीकर की माति सीनट ना नतन्त्र नहीं करता है। सीनेट म वाद-विवाद सम्बाधी इस परम्परा का विकास हुआ है कि अध्यक्ष दोना दलो ने साथ निष्यक्ष व्यवहार करेगा । सीनेट अपने मे से ही अस्थायी नध्यक्ष (President pro Tempore) को चुनती है जो अध्यक्ष की अनुपहियति मे सीनेट की अध्यक्षता करता है। अस्थायी अध्यक्ष यद्यपि सीनेट द्वारा निवाचित होता है पर तु व्यवहार म वह यहमत दल की समिति द्वारा निवाचित किया जाता है एव प्रतिनिधि सदन क स्पीकर की भाति बहुमत दल का नता हाता है। ऑग एवं रे के अनुसार प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष की माति अस्यायी अध्यक्ष का पद दतीय है और बह बहमत दल के कायकम की आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता है।

विदिश काम'स सभा का अध्यन

ब्रिटिश कॉम स समा के अध्यक्ष का स्पोकर कहा जाता है यद्यपि वह कामन्म समा के बाद विवाद एवं विचार विमन्न म कमी कोई भाग नहीं लेता। वह जब कभी बोलता है तब लोकममा म नहीं अपितु लोकसमा की तरफ से बालता है। स्पीकर के पद की उत्पत्ति अतीत के गत म कि तीन है। उसका पद सम्मान, प्रतिष्ठा एवं सत्ता ना है। प्रथम ज्ञात स्पीकर का नाम नर थामस हगरकाड (Sir Thomas Hunger ford) था। वे 1377 ई म अध्यक्ष थे। प्राचीन काल म स्पीकर कॉमन्स समा का प्रवक्ता होता था। वह सदन की तरफ से राजा के समन आवेदना एव प्रावना-मना को प्रस्तुत किया करता था। इस पद का विशत 600 वर्षों य विकास हुआ है। प्रारम्म म स्पोक्र की नियुक्ति राजा द्वारा की जाती था । लेकिन अब स्पीकर निर्वाचित होने लगा है परातु इसके पश्चात भी जसाकोक (Coke) न 1648 ई म कहा है, 'परामरा यह बनी हुई है कि राजा किसी बाग्य एव विद्वान व्यक्ति को स्पीकर नामादित करता है और कॉम म समा द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है।' जाज तृतीय के कारी तक स्पीनर क निवाचन म राजा का प्रमाव होता था। आज भी स्पीकर ने निर्वाचन की राजा द्वारा स्वीकृत किया जाता है नेनिन यह कवल औपचारिनता मात्र ही है। तिदा तत स्पीनर या अध्यक्ष का निर्वाचन कामन्स समा द्वारा होता है लेकिन व्यव हार म प्रधानमानी किसी सुयोग्य व्यक्ति का मित्रमण्डल के सदस्या एव विरोधी इत र नता क परामद्या स चयन करता है। इसके पदवात काम स समा क सदस्यो द्वारा

⁸ Ogg and Ray op ett., p 202 १ वामन समा के युख प्रमुख स्त्रीकरा व नाम है—बीटर डी माउक्टकोड (Peter de Montford), सर समस मुर (Sur Thamas Moore), नर एडबड हुके (Sir Edward Cocke) एव सर बिलियम नियास (Sir William Lenthal)!

जसका नाम प्रस्तावित क्या जाता है एव दो वैयक्तिक सवस्य जसका समयन करते हैं। स्पीकर का निर्वाचन दलीय आधार पर होता है। सामा यत बहुमत दल के ही हाराज्य का नाम प्रस्तावित विया जाता है वैकिन विरोधी दल से इस सम्बन्ध म परामस जिन्नायत विया जाता है। जिस नाम के सम्बय म विराधी बस सम्मत य प्रथम आयामा ने इंस्ता है। एक साम को प्रस्तावित मही किया जाता है। इस नहां हाता है, जयानन ना आरा कर्य गान भा नत्त्वात्वय गर्थ (क्यून) भावा है। स्व परम्परा का उद्देश अध्यक्ष के निर्वाचन का संवसमाति से करना है। यद्यपि अध्यक्ष भरत्यरा मा जहरव जन्मत क गणाचा का वचकन्मत व गर्मा हा जन्मत जन्मत कर्मा विवास के प्रसाद कर्मा के प्रसाद कर्मा है। जाता है एव पूर्ण निप्पक्षता से आचरण करता है।

-i

\$

7

निष्पक्षता, निदनीयता एव स्यायित्व त्रिटेन क स्पीकर की युर्प विशेषताएँ हैं। वह निजयता स सदन के नियमा का पालन करता है और राजनीतिक दलदारी से अपन का प्रथम्पण पृथक रखता है। निर्वाचित होन के पश्चात स्पीकर राजनीतिक वल संप्राह्मेण सम्बंध विच्छत कर तेता है। चाल्स प्रवम के शासन काल में घटित एक पटना से उसकी निप्पक्षता पर प्रकास पहता है।10 चाल्स प्रथम (1625 1647) का ससद सं समय खिड़ा हुआ या। चाल्स ने 1642 इंस एक दिन कासस समा म पुसकर स्पीकर से पूछा कि उसका विरोध करन वाले विद्वाही पाच सदस्य कहा है ? र्वेषकर त्याकर त त्रेष्ठा व च्याचा व्याप व्य तत्कालीन स्पीकर तिमचाल (Linthall) न इस पर यह उत्तर दिया था कि "महाराज वरणातान स्वाक्तर विस्तान कि में सवक हैं के निवसन के अलावा मुक्ते बैसने देव स्थान पर जान वा ज्वाचा । जान वा जान हु जा वा वा प्राप्त उज्ज प्रवाद विद्वाद के नियम एवं ५व अध कहत के भार जान्य एवं भारत है। जिल्ला नबीन निर्वाचन में वह निविरोध निर्वाचित होता है। यद्यपि स्पीकर का निवाचन काम स समा की अविध के निर्प होता है परसु प्रट ब्रिटेन म इस परम्परा का विकास हुआ है कि स्पीकर जब तक बाहता हैं अपने पद पर बना रहता है। एक बार बच्चाल निर्वाचित हान का अब मृत्युपय त ज्यात जीवन मर के लिए अध्यक्ष नियुक्त होना है। वह स्वेच्छा स अपने पद स त्याग पन दे सकता है। उसक विरुद्ध निवायनों म कोई अ य प्रत्याची खडा नहीं किया जाता पत्र व चरचा है। जवक १५५% शत्राचारा च चार ज च तत्राचा ज्वा गरा सम्बन्धा जाता है। ११ यह परम्परा 1722 हैं में स्पीकर कोम्पटन (Compton) के समय से प्रारम्भ

¹⁰ Keir Sir David Lindsay The Constitutional History of Modern इस परम्परा का एक दोप यह है कि जिस निर्वाचन क्षेत्र सं स्पीकर चुना जाता

इत प्रध्यस्य का एक दाप यह है कि जिस तिवाचन क्षेत्र स स्थाकर चुना जीता है वह व्यावहारिक रूप से प्रतिनिधित्व से विचत हो जीता है। उत्त यह सुभाव दिया गया है कि बच्चक्ष एक कल्पित निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाये। जेतिन वसी दिया गया है। के बच्चदा एवं भारता । गया भग व ते व चुना थाय । वाक्य वस तक यह मुक्ताव निर्या बत नहीं ही सका है। फाइनर इस तक को कि निर्याचन थान आवानाचाद व वाचव हा बावा ह हात्मात्त्व बानवा ह। 1757 र म कॉम त समा की एव प्रवर समिति ने इस प्रस्त पर एक रिपाट की है। प्रवर कात व वर्गा का एवं अवर वाताव न इव अवर वर एक रहार व ह । अवर मिनित के ऐतिहासिक एवं वुवनास्तव शोध ना यह निस्तप है कि निर्वाचनसेव मागाव ४ (रावधावक ५४ प्रकारका चाप ४) ४६ ।गरूप है कि गावध्यक्त को भी अय सदस्या की भावि निर्वाचित

हुई है। 1895 ई म वालफोर ने स्पीकर मुली का विरोध करके इस परम्परा हो तोडने की धमकी दी थी लेकिन निर्वाचनों म अनुदार दल का बहुमत प्राप्त होन क कारण वालफोर ने अपने विचार को कियान्वित नहीं विया। 1935 ई म श्रम दल ने इस स्थापित परम्परा के विरुद्ध स्पीकर फिटजरो (Filzroy) को उम्मीदवार खडा निपा या नेकिन उसे केवल असफलता ही हाथ लगी थी क्यांकि अनुदार दल एवं उदार दल न पुराने न्यीकर का ही समर्थन किया था। 1839 ई म Shaw Lefevre सनप्रयम एक सभप में ही स्पोकर चुने गये थे। 1951 ई में भी स्पीकर के यद पर समय हुना था। इस समय ग्रम दल विरोधी दल या। अनुदारदलीय अम्मीदवार का विराध तो श्रम दल ने नहीं किया परन्तु यह प्रस्तावित किया कि मृतपून उपाध्यक्ष अपने व्यापक अनुभव के कारण एक योग्य उम्मीदवार है। अत मतदान हुआ जिसमें अनु-दारदलीय प्रत्याशी विजयी घोषित किया गया। सामान्यत स्पीकर के पद के लिए ऐसे प्रत्याकी का नाम प्रस्तावित किया जाता है जो दीघकाल तक शासन का सदस्य नहीं होता तथा सनिय राजनीतिज्ञ और साधन या अय समिति के अध्यन अयवा उपाध्यक्षके रूप म नाम करने का दीघकात का अनुमन रखता है। चूकि अध्यक्ष से पूण निष्यक्षता की आशा की जाती है जत यह आवश्यक है कि वह हर प्रकार के राजनीतिक कार्यों से दूर रहे। यह भी आवश्यक है कि उसे निर्वाचन म माग न सना पढ़े। अत इगलैण्ड का जनमत स्पीकर का निविरोध प्रन निवांचित करना अपना क्तव्य मानता है।

स्पीकर निष्पसतापूबक बाबरण कर सके इस हेतु निम्नलिखित परामराओं मा

विकास हुआ है

(1) स्पीकर सम्पूण सदन द्वारा निर्वाचित होता है एव 1722 ई त प्रस्थक स्पीकर एक वार निर्वाचित होने के पश्चात निर्विरोध निर्वाचित होता ग्हा है। प्रस्थेक स्पीकर का शीसतन कायकाल इस वय रहा है। स्पीकर जानस्सा (Onsisw) 34 वय तक पताब्द रहा था। इसवैष्ठ में स्पीकर काम्म की चाति एक सन क लिए मिर्च विवत नहीं होता। अब दीपकाल तक पदाक्ख रहने के कारण स्पीकर का निर्पाद हिंबति प्रातो है।

(2) स्पीकर मनसम्पति से विरोधी दल की विश्वास म तेकर निर्वाचित किया

जाता है। 1839 ई म इस प्रधा का विकास हुआ है।

(3) स्पीकर निर्वाचिन होन के पश्चात पुणक्षेण निर्दास हो जाता है। वह समस्त बलीय सम्बन्ध तोड लेता है, दल की बठका य भाग नहीं सेता, दत्तीय नीर्ति के सम्बन्ध में निचार व्यक्त नहीं करता और न अपने निर्वाचन-श्रव का ही ध्यान रसता है। राजनीति से वह पूणक्षण निरुषक्ष हो जाता है।

विया जाना चाहिए। इसमें उसमें एवं बाय सदस्यों ये एक प्रकार की समानता आती है।' — Fince, Hop cit, p 476

10

व्यवस्यापिका—विधि निर्माण प्रक्रिया एव सम्विधित विषय | 361 (4) वह सदन के वाद विवाद म माग नहीं नेता । उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है लेकिन उसके द्वारा इसका प्रयोग प्राय नगण्य ही है 1 यदि कमी कोई अवसर आता भी है तो ययास्थित वनाये रखने के लिए परम्परानुसार ही वह अपना मत देता है जिससे सदन म समस्या पर पुन विचार हो सके।

; ,

٢

f

स्पीकर के काय एव वायित्व स्पीकर काम स समा की अध्यक्षता एव उसका सामृहिक रूप सं प्रतिनिधित्व करता है। सदन एव लॉडसमा एव लॉडसमा तथा मंग्राट के मध्य नहीं वार्ता करता है। वह सम्मेलना एव औपवारिक समारोही म सदन का प्रतिनिधित्व करता है। वह सदन एवं उसके सदस्या के विशेषाधिकारा एव विधिकारा का सरक्षक है। व्यक्तिगत सबस्या के हितो का भी वही सरक्षक है। सदन म अनुसासन एव व्यवस्था कायम रखना उसका प्रथम कतव्य है। आवश्यकता पडने पर अनुवासन मग एव बाजा का उल्लंघन करने वाले सबस्या की वह कॉम स समा स निकासित करने का अधिवार रखता है। वह काम स समा का प्रवक्ता (Spokes man) होता है। वह तदन के नाम प्रेपित तभी स देशा की प्राप्त करता है एवं तदन के आदेशा को किया वित करता है। उसकी हिन्द म सभी सदस्य समान होत है।

वह सदन म वाद विवाद सम्बन्धी नियमो एव औचित्य के प्रश्ना (Points of Order) को कियाबित एवं निश्चित करता है। सदस्या को प्रका प्रशास ज वहीं प्रदान करता है एवं सदन म मतदान की व्यवस्था तथा उसके आधार पर निषय

वह कॉम स समा की मिनया (procedure) निवारित करता है एव आवश्य-कतानुसार तत्मान्यभी नियमो की व्यास्था करता है। वह स्वय वाद विवाद में माग मही लेता लेकिन गतिरोध की स्थिति में निर्णायक मत देता है। वह बाद विवाद मे सदस्यों को माग लेने का अवसर प्रवान करता है। प्रस्तुत संशोधना को विचार विमय हैंदु नहीं चयन करता है। पुनरावित एव अनावश्यक संशोधना एव प्रश्ना को रोकता है। प्रश्नकाल (Question bour) के प्रचात प्रस्तुत तात्कालिक सावजनिक महत्त्व के प्रका पर काम रोको एव स्थाय प्रस्तावो को स्थीकृत एव अस्थीकृत करन का उसे अधिकार प्राप्त है। तात्कातिक सावजितक महत्व के सम्बन्ध म उसका निणम अतिम एव निर्णायक होता है। 1923 ई के बाद सं स्पीकरो ह्वारा वात्कालिक सावजनिक महत्व सम्ब धी वायित्वा की एसी सुनिध्चित व्याख्या की वा रही है कि सामा य सदस्या के लिए इन प्रस्तावा के माध्यम सं सरकार को चुनोती दना प्राय असम्मव हो गया है।22

ए. वह सदस्या क मापण के अधिकार को स्वीकार करता है। अस उसका यह दापित्व है कि सदन के सभी प्रतिनिधि वर्गों एवं हिता का जपलब्ध समय म विचार 12 Finer, H op at, (Footnote N 4), p 476

व्यक्त करन ना अवसर प्राप्त हो जाय। वावस्यक एव विलम्बकारी प्रस्तावा को वह अस्वाकार वर सकता है।

अध्यक्ष के द्वारा ससद व प्रारम्म म ही नुछ सदस्यों की एक मूची त्यार की जातों है। इनम स वह स्थायी ममितियों के अध्यक्षा का चयन करता है एवं यह निद्वित करता है कि विभेयक किस समिति म विचार हतु भेजा जाय।

शासन स पूछे जाने वाल प्रस्ता का वह भौचित्य क अनुसार नमन्द्र रूप से व्यवस्थित करता है एव पूरक प्रस्ता क लिए समय निश्चित करता है। उस वितीय विषेयका को प्रसाणित करने का भी अधिकार प्राप्त है।

समीमा--विटिश बच्चास का पर सम्मान का है। उसस यह पाधा नी जाती है कि वह यायाधीश जेमी निष्यक्षता से काम करेगा। बच्चास पद के लिए म्लेडस्टीन के अनुसार ' उस यक्ति को चुना जाना चाहिए जिसका वल म काई यिग्नेय प्रमाव ने हा क्यांकि ऐसा न होने पर महानिक आपत्तियों हाती रहणी और अध्यक्ष को पढ़ स्तपात विवाद का विषय वन जायेगा।" जेनिस्स की हिट में अध्यक्ष की पाय उसके उसने उसने बीम के प्रमाद नहीं करती विसका वह उपयोग करता है।" अग्य एव जिस की हिट में अध्यक्ष की हिए में अध्यक्ष के प्रमाव प्रमाव करता है।" अग्य एव जिस की हिट में स्वीकर को अपना एवं मुझ्मीयों होना चाहिए। उसनी वाणों तेज एवं स्वयात अहकारी होने के साथ ही उस धनी, व्यापु मोपा, सत्रन, प्रमावन पद ध्वाद पुर्वेश होना चाहिए। स्पीकर का हम 'वनाम ममा की काय प्रमावन पद ध्वाद के अपने से ही रक्षा करना है और वाद विवाद के अनुसार उसका काम सदन की अपने से ही रक्षा करना है और वाद विवाद के समय अब वह अध्यक्षता करता है तब इस दायित की विशेष स्थ ने निमाता है।" स्वीकर 'वाद-विवाद का जांड है। यह ध्यान एवना उसका हो हो स्विद्य के है। स्वाप्त का विषय पर ही बाद विवाद के है।

^{13 &#}x27;It is impossible however to indicate by enumeration of powers and immunities the prestige which the Speaker enjoys '- Ivor Jennings The Parlament 1970 p 70

¹⁴ Ogg and Zink op est p 248
15 Gladstone cited by A C Kapoor op est p 163

स्पीकर के पद एव दायित्वा को ब्यक्त किया है "में देवने का प्रयत्न करता हूँ कि सम्पूण यान मती प्रकार चन रहा है। स्पीकर अपने पद में एवं पद के अतिरिक्त इसमें सहायना कर सकता है। मेरा काम यह देखना भी है कि बासकीय काम, जिसके लिए में उत्तरदायी नहीं हूँ, के भाग म जानवुक्त कर वाधाएँ उत्तन नहीं की जानी हैं। मेरा काम यह देखना भी है कि अत्यसस्यका के विचार मुने जाते हैं। जब भागण देने के लिए वक्ताओं के नाम लिये जाते हैं तब सदन के सभी प्रकार के विचारों का उचित अवसर मिल सके, इसका मुक्त ज्यान रखना पहता है। सभी को स्वतन मामण के उचित अवसर मिल सके, इसका मुक्त ज्यान रखना पहता है। सभी को स्वतन मामण ने उचित अवसर प्राप्त हो सके, यह मेरा वायित्व होना चाहिए। में अध्यक्त के नाते ने सरकारी और न विपोधी दल का ही सदस्य हूँ। मैं कांम स समा का ब्यक्ति हूँ एवं उसकी रक्षा करने का इच्छुक हूँ तथा उसकी रक्षा में कर्षेग।"18

अमेरिकी प्रतिनिधि सदन का अध्यक्ष

सिवधान प्रतिनिधि सदन को अपना स्पीकर एव अ य अधिकारियों के चयन का अधिकार दिया गया है। 17 अमेरिकी प्रतिनिधि मदन के अध्यक्ष पद का विकास 18वीं मदी के ब्रिटिश अध्यक्ष के परम्परा पर हुआ है। लेकिन वह त्रिटिश अध्यक्ष के पर स पूणाम्परा मिन के किया है। लेकिन वह त्रिटिश अध्यक्ष के पद स पूणाम्परा मिन समा है। अमेरिकी प्रतिनिधि मदन का अध्यक्ष करेंगा स मना के अध्यक्ष की माति स्वन के नियमों की धोपणा मान ही नहीं करता वर्ग सदन के नियमों को स्वेचकों में ति स्वार्थ का निर्माण भी करता है। स्परणीय है कि समितियों का ध्यवहारत मदन के काथप्रदित पर अधिकार होता है। सरणीय है कि समितियों का ध्यवहारत मदन के काथप्रदित पर अधिकार होता है। स्वेचक के अनुसार, "20वीं सदी के प्रारम्भ म अर्थात 1910 ई तक सदन की निवंदान होता होता है। बीधड के अनुसार, "20वीं सदी के प्रारम्भ म अर्थात 1910 ई तक सदन की निवंदान होता वा पा उसका मदन पर निरकुत्र नियन्त्रण होता या।' अकिन अन वह समय नहीं है जब स्पीकर निवास कियों निवास का प्रयोग मर मके। वह नियम समितियों के वब हटा दिया गया होत वो प्रमस्त समितिया मी निपुत्ति करने ही धीं मिन स्वित से से अध्यक्ष प्रवास कर हो धीं में स्वत्य समितिया मी निपुत्ति करने प्रवित्य स्वत्य समितिया मी निपुत्ति करने प्रवित्य स्वत्य के शान स्वत्य समितिया मी निपुत्ति करने ही धीं मिन स्वत्य समितिया मी निपुत्ति करने प्रवास कर हो धीं मिन स्वत्य समितिया मी निपुत्ति करने प्रवास कर हो धीं मिन स्वत्य समितिया मी निपुत्ति करने प्रवास कर हो धीं में स्वत्य समितिया मी निपुत्ति करने प्रवास कर हो धीं में स्वत्य समितिया मी निपुत्ति करने प्रवास कर हो धीं समस्त समितिया मी निपुत्ति करने प्रवास कर हो धीं स्वत्य स्वत्य समितिया मी निपुत्ति करने प्रवास कर हो धीं समस्त समितिया मी निपुत्ति करने प्रवास कर हो धीं समस्त समितिया मी निपुत्ति करने प्रवास कर हो धीं समस्त समितिया मी निपुत्ति करने प्रवास कर हो धीं समस्त समितिया मी निपुत्ति करने प्रवास कर हो धीं समस्त समितिया मी निपुत्ति करने प्रवास कर हो धीं समस्त समितिया मी निपुत्ति करने प्रवास करने स्वत्य समस्त समितिया मी निपुत्ति करने प्रवास समस्त समितिया मी निपुत्ति करने प्रवास कर हो धीं समस्त समितिया मी निपुत्ति समस्त समितिया मी निपुत्त समस्त समस्त समस्त समस्त समस्त सम्वत्य समस्त समस्त समस्त समस्त समस्त समस्त समस्त समस्त सम्त

प्रतिनिधि सदन की अन्यक्षता के लिए प्रत्यक नवीन काग्रेस का सप प्रारम्म

¹⁶ Chiton Brown, cited The United Kingdom Constitution, BIS RF, p 4758/68 pp 24 25

¹⁷ Article 1, sec II, cl 5 of U S Constitution

At the opening of this century, the directing power in the House was unquestionably concentrated in the speaker. The majority members of the Rules Committee (of whom the Speaker was one) and the Chairman of the important committees were appointed by the Speaker.—Prof. Beard. quoted by Mahajan V. D. op. ct., p. 179

होनं पर उस बहुमत दस वे कानस (Caucus) द्वारा मनोनीत निया जाता है एव बहुमत के आधार पर सदन द्वारा औपचारिक रूप म निर्वाचित किया जाता है। सदन म जिस दम ना बहुमत होता है अनिवायत उसी दस का प्रत्यायी स्पोकर निर्वाचित होता है। हिया जाता है। सदन म जिस दम ना बहुमत होता है अनिवायत उसी दस का प्रत्यायी स्पोकर निर्वाचित होता है। विदेश स्पोकर की माति निवाचन के पहचान अपन दतीय स्वरूप ना परिस्थान मीनरी किरता जोर ति से विदेश स्पोकर की माति निवाचन के पहचान अपन दतीय स्वरूप ना परिस्थान मीनरी किरता जोर दिनीय कार्यो एव समाठन म मिन्य माग तेता रहता है। वह दम का चार्तिकाशों नेता होता है। विदेश स्पोकर की माति नह अपने पर पर वार बार निर्वाचित नहीं होता है। प्राय हर निवाचन के परचात प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष वदलते रहते है। प्रतिनिधि सदन म स्पीकर अपन दस का घोषित अमिनकों होता है और वहा की दलगत राजनीति म वह सिन्य माग सेता है। अस विदेश स्पीकर की माति उसके निष्पक्ष होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वह सदन के कार्यों म अपने दल को हर मनमन सहायता पहुँचान न निष्प प्रयत्यदीत रहता है। अपने दलाय कायनम को अपसर करन के लिए वह सिन्य रहता है एव इस हें सु आवस्यक विधियों के को असर करन के लिए वह सिन्य रहता है एव इस हें सु आवस्यक विधियों के निमाण म योग देता है। स्पीकर सदन का महत्वपूष अधिकारी होना है एव उसकी स्थिति के बीध होनी है।

स्पीकर के काय एव वाधिस्व¹⁰—स्पीकर सदन की अध्यक्षता करता है, सदन की बेटका को प्रारम्भ एव समाप्त करता है तथा वह सदस्यों का विवार आफ करते की अनुमति प्रवान करता है। सामाप्त उसके डाग्र किसी विवयक पर पड़ते पढ़ों में जमा बाद म विवक्त कर मा अनुमति वी वासी है, लेकिन अपने दत्त के सदस्यों को वह अधिक अवनार प्रदान करता है। वाद विवाद की अवस्था एव सदन म अनुमान एव अथस्था वनाये रखना उसी का दायिक्य है, लेकिन अपने दाकर म अनुमान एव अथस्था वनाये रखना उसी का दायिक्य है, सिक्त ब्रिटिंग स्थाकर की मावित उस मदस्या का दिव्हत करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। सदन को ही किसी सदस्य को प्रविच्त करने का अधिकार होता है। अथ्यवस्था एव सदस्यों डाग्र हिंदी भी की दशा में वह सदन नो स्थापत कर सवता है या सार्जेस्ट को अथवस्था स्थापित कर सवता है या सार्जेस्ट को अथवस्था स्थापित कर सवता है।

समितियों के सदस्यों को भी उसक द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। 1911 ई तक वह नियम मिनिन (Rules Committee) एवं समस्त स्थायों समितिया ने सन्दर्भों को नियुक्त करता था जेकिन अब उसे केवल प्रवर एवं विशेष समितिया अववा प्रतिनिधि सभा द्वारा अधिकार प्रदत्त किये जाने पर समितियों के मदस्यों को नियुक्त करने ना अधिकार प्राप्त है इसके अतिरिक्त यदि किसी विधेयक को सिनित में भेजन के सम्बन्ध में कोई मतमेद होता है तो ऐसी अवस्था में स्थीवर का निष्य अतिमाता जाता है। वह सदन ने निष्या क्याया करता है तथा उन्हें किया

¹⁹ Ogg and Ray op cst, p 200 and Herman Finer op cst, pp 477 478

व्यवस्थापिका—विधि निर्माण प्रत्रिया एव सम्विधत विपय | 365 वित करता है। सदन को उसकी व्याख्या को बहुमत से अस्पीकार करने का अधिकार प्राप्त है। वैकिन सदन ने अपने इस अधिकार का बहुत कम प्रयोग किया है। अव आत हा ताकृत वस्त न अवत् वर्ष आवकार का बहुत कर्म अवाग क्या हा अव काम सं समा के अध्यक्ष की मौति प्रतिनिधि सदन के स्पीकर द्वारा की गयी व्यास्था वितम नहीं होती है।

स्पीकर को अपना मत दने एव वरावर मत आन पर निर्णायक मत देने का अधिकार है। वह अपना मत गुप्त मतदान की अवस्था म ही देता है। सामायत जायकार हा वह अपना यत गुज्ज यतमात्र का जवस्या न हा यता हा जाना यत स्योकर मत बेन के अधिकार का प्रयोग नहीं करता। वह सदन के विचाराथ उपस्थित प्रस्त पर मत विमाजन कराता है एवं उसके श्रीधार पर निगय की घावणा करता है। नरन ४९ भवा वसाजन करावा ह एवं जवक आवार भरावणव का वावणा करावा है। बहु सबन द्वारा पारित सभी विषेयका एवं सदन द्वारा निर्वेशित संयुक्त भस्ताको, विता एव आवेशा पर हस्ताक्षर करता है। आवस्त्यक्ता समभने पर वह वीर्घाओं को

वह अपनी अनुपस्यिति म सदन की बिना अनुमति के किसी भी अस सदस्य वह अपना जाउपारवाच न चवा का त्वाम जाउगाच मा महाचा ना जाव प्रवास को अध्यक्षता करने के तिए अधिक ते अधिक तीन दिन एवं अस्वस्थता की अवस्था म का अध्यक्षता करत का ताए आवक व वावक वाग विष एव व्यवस्थवा का व्यवस्थ है। विकिन व्यवहार म वह अय व्यक्तियां को अध्यक्षता करने के तिए अस्थायी रुप स

समीक्षा-स्पीकर प्रतिनिधि सदन म अपने दल का नेता होता है। सुप्रक्त राज्य अमरिका म शक्ति-पृथवकरण के सिद्धांत के अनुसार कायपालिका व्यवस्थापिका ते प्रयक्ष रीति स सम्बर्धित नहीं होती। अत वह सदन म अपने ही दल का प्रति-निविद्ध नहीं करता अविद्ध निद्धि निविद्ध निवास के तेरह सदन का नेतल्ब भी करता है। यदि राष्ट्रपति एवं स्पीकर एक ही दल के होते हैं वो स्पीकर अक्सर राष्ट्रपति हा नार राष्ट्रपात एवं स्वाकर एक हा बल क हात है वा स्वाकर अवस्य राष्ट्रपात वे परामय करता रहता है और उत्ते व्यवस्यापिका (प्रतिनिधि सदन) म प्रशासन का अधिकृत प्रवक्ता माना जाता है।

सविधान म मतिनिधि सदन के भा तरिक सगठन के सम्बन्ध म केवल इतना कहा गया है कि सदस्य स्पीकर एवं अस्य अधिकारियों को नियुक्त करेंगे। उसकी प्रशास है कि सबस्य स्थाकर एवं का व वायकारचा भा 1230 करना। ज्यक वितियो एवं कतव्या है तारे म सविधान म कोई उल्लेख नहीं है। सविधान क अनु सार यह भावस्यक मही है कि स्पीकर सदन का सदस्य हो। वेकिन प्रारम्य स ही प्रत्येक स्वीकर अपने निर्वाचन के समय सदन का अनिवायत सदस्य होता रहा है।

अमेरिकी स्पोकर बिटिस स्पोकर की मांति निदलीय एवं निष्पक्ष तथा याय-प्रिय (Judicious) नहीं होता । यह बलीय व्यक्ति है एवं अपने देन की पूरी सहायता भित्र (Junus) गहा हात । वह वचाव व्याप्त ह एवं जगा वच का पूरा वहायता करता है। इसका एक प्रधान कारण है। प्रतिनिधि सदन में अधिकृत नेतल 20 Ogg and Ray op eu, P 201

10

÷

. +1

,

²¹ Ogg and Ray op at P 201

(official leadership) का अमान ह । सिन्धान-निर्माताजा की धारणा थी कि सदन अपन नेतत्व की समस्या का समाधान स्वय कर लेखा । सदन की सदस्य मह्या प्रव का प्राप्त मार्थ मृद्ध के साथ नंतृत्व की आवश्यकता को भी अधिकाधिक अनुमव किया जाने लगा था एव वहुमन दल का प्रमुख सदस्य होन के कारण यह दाधित्व स्पेकर के का पा पर यह है । हैनरी के समय से ही स्पीकर वहुमत दन के सदस्य होने रहे है और इस कारण जह सदस्य होने तरहे है और इस कारण जह सदस्य को नेता माना जाता रहा है । मुनरों के अनुसार स्पीकर हो वह व्यक्ति था जिम पर बहुमत दल अपने विधि प्रस्तावों को नियमा के जाना स सरकतापुष्टक पारित कराने के लिए निजर रहता था। फलत उनके हाया में अविक स अधिक कार्कि के दिल होने लिए निजर रहता था। फलत उनके हाया में अविक स अधिक कार्कि के दिल होने लगी है और वह वास्तव म एक तानाप्राह बन गया है। वै आँप ने इसी विचार को व्यक्त करते हुए कहा है कि "एक तानाप्राह बन गया है।" अर्थ ने इसी विचार को व्यक्त करते हुए कहा है कि "एक तानाप्राह सन गया है।" उन्हां स्वय बार सम्मादित किय जा सकने वाले हर निपय म उन जीवन एव सरण की शिक्त प्राप्त हो गया है और वह वास्तव मार्थ है प्राप्त हो साथी है हो उन्हां से इसके प्रव हो सिन मार्थ है। उन्हां से वित होरा नित है।" अर्थ प्रव स और चित हो सिन सिन है।" वित हो सिन है।"

²² Speaker 'became the man on whom the majority depended for getting its measures safely through the maze of rules More and more authority was absorbed into his hands until he became a virtual dictator '---W B Munro The Government of the United States op cit, pp 324 325

²³ A simple chairmanship grew into a vital dictatorship, carrying the power over life and death over almost everything that the House undertook to do —Ogg cated by Mahajan, V D Select Modern Governments 1964 p 180

²⁴ Ogg and Ray of cit p 201

²⁵ Finer, H op at p 480

व्यवस्थापिका—विधि निर्माण प्रत्रिया एव सम्बर्धित विपय | 367 सिमिति सं स्पीकर को हटा दिया गया तथा सभी स्यायी सिमितिया को नियुक्त करने का अधिकार सदन को प्रदान निया गया। मायता (recognition) की सक्ति उसस ते तो गयी। फतत स्पोकर की शक्तियाँ काफी कम हो गयी लेकिन आज भी स्पीकर सदन का प्रमुख अधिकारी है।

हरमेन फाइनर कं अनुसार, "स्पीकर आज भी यपाधत दलीय व्यक्ति है। वह नीयस के योहे से नेताओं में से एक हैं जो प्रचासकीय विधयका का पास्ति करने के तिए राष्ट्रपति सं तम्पक स्थापित करता है। आज भी दलीय संचातक समिति (Steering Committee) उससे परामच करती है। उसका दल म वडा प्रमाव है। आज मी वह समितिया क मध्य काय विभाजन एवं उनकी प्राथमिकता के निधारण के सम्बाप म स्वापक शक्ति रखता है। इसी कारण वह स्पोकर भी चुना जाता है। 435 सदस्या के प्रतिनिधि सदन म व्यवस्था तथा काय प्रणाली के लिए कही न कही तो नैतृत्व का होना आवस्यक है ही। 1910 ई तक वह शक्ति स्पीकर एव उसकी क्रपा ते उसके मित्रा म निहित थी। बाज वह स्पीकर के मित्रा एव स्पीकर म के दित है। भव नतत्व को समितिकृत (syndicated) या समूहकृत कर विया गया है लेकिन स्पीकर समिति का आज भी प्रमुख सदस्य होता है। अ बिटिश एव अमेरिकी स्पीकर की तुलना

जिहिस स्पीनर की तीन मुख्य विशेषताएँ हैं—निष्यक्षता, निदलीपता एक स्थापित्व । लेकिन अमरिकी स्पीकर की यह विश्वेपताए नहीं होती है। वह निर्वाचित होते के पहचात दलीय सम्बंधी का परित्याम नहीं करता, फलत्वरूप वह निजयस नहीं हैं और उसका पद मी स्थायी नहीं होता। प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात नया स्पीकर निर्वाचित किया जाता है।

निर्दिश स्पीकर की माति प्रतिनिधि सदन के स्पीकर का निर्वाचन भी निर्वि वाद नहीं होता। अत्तएव उसके लिए अपने निविचको की उपेक्षा कर सकना सरल नहीं है। प्रतिनिधि सदन में बह सदन के नता की भूमिका निमाता है एवं कॉम स समा क स्पीकर के निपरीत वह बाद विवाद में माग लेता है तथा आवश्यकता पडने पर अपने मत का भी प्रयाम करता है। काम ससमा का स्पीकर केवल निषायक मत रखता है। जिसका भी प्रयोग वह स्यापित परम्परा क अनुसार यथास्थित वनाये रखन क लिए ही करता है।

'काम स समा का स्पोकर केवल नियमों की घोषणा करता है चाहे वे अल्प-संस्यको के हित म हो अथवा अहित म । प्रतिनिधि सदन का स्पीकर नियमों की व्यास्या करन म पर्योत्त स्विविवेक का प्रयोग करता है।' छाइनर के अनुसार आज स्पीकर अपने दल के प्रमुख नेवाया म ते होता है। 1911 ई के पूब वह व्यवस्थापिका म दल 26 Finer, H op cut, p 480

का प्रमुख नेता होता था। [?] ब्रिटिश एव अमेरिकी स्पीकर की विभिनताएँ महलपूर्ण है। 'दोनो हो अपनी सम्पूण राजनीतिक प्रणालिया के लघु रूप है।'' ⁵

कनाडा, आस्ट्रेलिया एव न्यूजीलैण्ड के स्पीकर

इन देशों में त्रिटिश संसदीय प्रणाली का प्रमाव है क्योंकि वे सभी त्रिटिश औपनिवंशिक देश है। उनके सविधानों का स्रोत त्रिटिश संसद है।

उपरोक्त तीनो देशों में शासन मं परिवतन के साथ अध्यक्ष पद म भी परि वतन होते हैं। बहुमत दल का स्पीकर पद पर प्रभाव होता है। ब्रिटन में स्पाकर के निर्वाचन म उसका विरोध नहीं होता। लेकिन इन देशों में इस परम्परा का अनुगमन नहीं किया जाता है।

जब सदन का सिमिन क रूप में खिंचवान होना है तो इन देशा म स्पीकर बाद विवाद में भाग लेत हैं एवं मनदान भी करते हूं। इतना होने पर भी इन देशा में स्पीकर की निप्पसता के प्रति म देह नहीं किया जाता है। मसद के सभी वर्गों एवं इसों का उस पृण समयन प्राप्त होता है। फिर भी स्पीकर के निषय के विरुद्ध कमा-कभी रन देशा के सदनों मं मनदान हुए है। बिटेन की भाति इन देशा म एवं दिग्यीं अफीका म स्पीकर पद सं पृषक होने के पश्चात सिक्य राजनीति के अवकाश प्रहण नहीं करने हैं नयांकि इन देशा म स्पीकर के पद का राजनीतिक जीवन की सर्वोच्च परिपार्ति नहीं माना जाता है और नहीं स्पीकर पद से पृषक होने के पश्चात मंत्री पद प्रहण करता अस्वामाविक सम-का जाता है।

फास मे अध्यक्ष का यद

ततीय फच गणराज्य के निम्न सदन चेम्बर आफ डेयुटीज एवं चतुव 'गणराज्य' के निम्न सदन राष्ट्रीय समा के अध्यक्ष की स्थिति अमेरिकी स्थीकर की अरेशी निदिश्य स्थीकर से अधिक मिलती है। का सीमी अध्यक्ष भी बिटिख स्थीकर की मांति सवर्गय प्रणाली की उपज है जिसके अ तर्गत उत्तरदायी मां त्रिमण्डल को मांगरदान एवं निय त्रिय को सीमिक प्राप्त होनी है। अत कास में वन परिस्थितियों का अभाव है जिनके प्रमाव क कारण अध्यक्ष का हिस्कोण दसीय एथ यथावतपूण हो जाता है। लेकिन फाइनर के अनुसार ग्रेट ग्रिटेन की तरह का च म वे सब परिस्थितियों नहीं पायी जाती है। लेकिन प्रमाव के अनुसार ग्रेट ग्रिटेन की तरह का च म वे सब परिस्थितियों नहीं पायी जाती है जिनके परस्वस्थ का सोमी अध्यक्ष ब्रिटिख स्थीकर की योग्यता एवं निष्पक्षता वा पायन कर सक । 20

8 "Each speakership epitomizes a whole political system"—Finer, H op cit, p 480

29 Finer, H op cat p 481

^{27 &}quot;He ii today one of majority party leaders, before 1911 he was the party leader in the legislative branch of the government "-Finer, H op cit p 477

28 "Fack readership entrement and below the state of the stat

तवीय फ़ासीसी गणराज्य के निम्न सदन—चेम्बर—के हर नये सन का नया अध्यक्ष समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चुना जाता था। 6 अध्यक्ष मी इसी रीति से निर्वाचित होते थे जो वरिष्ठता के नम म अध्यक्ष के पद को रिक्त होने पर बहुल करते थे। चतुय गणराज्य म भी इस परम्परा का अनुगमन किया गया था। प्रति नवीन सत्र म नय अध्यक्ष के निवाचन का कारण पंच जनता की स्थापित अधिकारियां के प्रति परम्परागत अविश्वास की घारणा है। विधि-निर्माण स दक्षता की हिन्द से यह व्यवस्था एक बहुत वडी कमी है। हर नवीन सन के साथ निर्वाचन की सरगर्मी प्रारम्म ही जाती थी और दलीय त त्र उसम ध्यस्त हो जाता था तया अध्यक्ष के दोष एव गुण निर्वाचन की सरगर्मी म वर्चा का मुख्य विषय वन जाते थे। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष को अपने निर्वाचको को प्रमानित करते के लिए पर्याप्त समय प्राप्त नहीं होता था। अस्य कायकाल कं नारण अध्यक्ष की अपने काय का पूरा ज्ञान मी नहीं ही पाता था। इयलण्ड में 1872 ई से 1945 ई तक के समय में केवल 6 स्पीकर पदासीन हुए जब कि इसी काल म का स म 15 अध्यक हुए। का स म बहुदलीय पद्धति का ततीय एव चतुष गणराज्य काल म प्राधा य था। फलस्वरूप अन्यक्ष वधुवनाय प्रकार प्रमाणिक का होना स्वामाविक था और यह ऐसी भवस्या म और भी कठिम होता था जबिक पूण बहुमत प्राप्त होने पर भी दुवारा मतदान (second ballot) की व्यवस्था थी।

फात क ततीय गणराज्य म नेम्बर एव सीनेट तथा चतुष गणराज्य म अस म्बली एव कार्जसल (Council) के अध्यक्षा ने राष्ट्रपति के सहयोग से मिनमण्डलो के निर्माण म महत्वपूण भूमिका निमाधी थी। अपने दला स उनक सम्बच रहत थे। व निविरोध निविचित नहीं होते थे। दलीय वठका म भी वे सहयोग करते थे एव कभी कमी तो समाचार पत्रा म होने वाले निवादो म भी भाग लेते थे। अध्यक्षा द्वारा मनी पद प्रहण कर लिया जाता था एवं संत्री पद संशोधक पद पर व पुत लीट आत थे। यद्यपि जनके द्वारा बाद विवादा म दलीय हिप्टिकीय से हस्तक्षेप नहीं किया जाता था पर तु वे दतीय विचारा एव कार्यों तथा मावनावा को उमार देते थे। 1929 ई म कास म एक षटना पटी थी जिसकी इगलण्ड म गल्पना भी नहीं की जा सनती। उस समय केम्बर के अध्यक्ष मो होरियो थे। उन्होंने यकायक यह निश्चय किया कि रे शासकीय आदशा द्वारा विधि निर्माण की शस्ति प्राप्त करने के धासन के प्रयत्ना का विरोध करेंग और बिना किसी पूर्व मूचना के यकायक वे अपने स्थान पर पहुंच एव उनके मायण ने सरकार का वस्ता पनट विया। राष्ट्रपति द्वारा उह नयी सरनार बनाने वे लिए आमिनत किया गया। फर्नाण्ड वाइस्सन (Fernand Bonisson) 1926 ई स वेस्वर के अध्यक्ष थे। जहीन प्रधानमंत्री वनन के लिए अपन पद से 1935 ई

370 | आधुनिक शासनतः त्र

म त्यागपन दे दिया था । फाइनर व अनुसार, ''नेम्बर की अध्यक्षता गणरान्य क राष्ट्रपति पद वे लिए सीढी थी। 20

भेच विधानमण्डला क न यथा का त्रिटिश स्पीकर के समान ही राक्ति शान होती है। लेकिन कव व्यवस्थापिका म अनेक दत्ता क कारण स्पोक्तर का सांगित अपेक्षाकृत रुक्ति हो जाता है तथा एच समद म अनेक ससदीय आयोगी की जप हिसान उसके थाय को और भी अधिक कठिन बना देती है। इसके अतिरिक्त पर सम्बंधी परम्परामं उसका बनीय स्वक्ष एवं ससदीय जीवन की अस्थिरता के एस स्वरूप अध्यमा का काय और भी जीवक कठिन हो गया है। सदन म व्यवस्वा के लिए पण्टी बजती रहती थी लिहन कोई सदस्य उस पर ध्यान नहीं देवा था। इन सब को जह म तदस्या म पाप्त यह मावना थी कि वे तम्म मु है। इसके अतिरिक्त दिवीय

विभेद एव राज्य मिक्त का जमाव इस जनुत्तरदायित्व की मावना के अस कारण थे। चतुव गणराज्य की राष्ट्रीय समा के नियमा के कारण अध्यक्ष की स्पिति और मी कि हो नियो थी। उसको गीकिया तो प्रदान की गयी थी लिकन उसकी सता हो वस दिया गया था। सम्मनन का आहत करने विधयका को गणराज्य परिवर (Council of Republic) हारा पारित होन पर राष्ट्रपति को उह भीपत करते हेंचु प्रित करने और प्रेपित विषेयक को यदि वस दिन ही चुके हो तो उसे विषय स्थान मीपित करते अनुसासन मग करने वाले सदस्या को दण्ड देने एवं असम्देशी की रक्षा करत वाली सिनक टुकडी को अध्यक्ष के नियंत्रण म देकर उसे कुछ ऐसी ग्रासिय प्रदान की गयी है जो फाइनर के अनुसार कोई दुवृद्धि अध्यक्ष थीर सकट के समय प्रयोग करक शासन के माम में वापाएँ जत्य ने कर सकता है। विचय गणरास्य के अध्यक्ष का इस ऐसे दायित्व लींपे गये के वो किसी देश के अध्यक्ष को प्राप्त मही है जहें कि जिस्कारी के विषदम की माग करने के पूर्व मा निमण्डत को असम्बनी के अध्यक्ष से परामक करना चाहिए (अनुक्छद 51)। असम्बेली के स्य हो जाने पर प्रधानमं नी तो अपने पद से पृथक हो जाता था। विकिन मिनमण्डल बना रहता या जिसकी अध्यक्षता असेम्बली का अध्यक्ष करता था। तब निर्वाचना तक वह धासन की देखमाल करता था। उस मिनिमण्डल म नवीन गृहम नी एवं उन सव तमुहो म म राज्यमानी नियुक्त करने का अधिकार होता या जि ह मनिमण्डल मे का पद किसी कारण स रिक्त होने पर नविन्युक्ति तक वह गणराज्य के राष्ट्रपति के 30 Finer H op cut p 481 31 Finer H op cut p 482

³² पीचन फर गणराज्य के में तमत बच्चात की स्थिति में केवत यह परिवतन हुआ भागव काम गंगराव्य के व तामव बच्चक का तस्याव के कवत यह गर है कि जब क्रमस विभागमण्डल व कायकाल व लिए चुना बाता है।

भारतीय लोकसभा का स्पोकर या अध्यक्ष

ब्रिटिश बॉमन्स समा की मौति नवीन भारतीय लोबसमा अपने म से एक सदस्य को अध्यक्ष चूनती है। अ वह उसके अधिवेशना की अध्यक्षता एव सदन के काय का संचालन करता है। सदन एक उपाध्यक्ष को भी निर्वाचित करता है और वह स्पीकर की अनुपस्थिति म उसके कतव्या का सम्पादन करता है तथा सदन की अध्यक्षता करता है।" स्थोरर का 5 समापतिया को भी नामजद करने का अधिकार प्राप्त है जो उसके एवं उपाध्यक्ष की अनुपरिषति में सदन की अध्यक्षता करते हैं।³² स्मरणीय है कि इगनण्ड म काई उपाध्यक्ष नहीं होता । वहाँ सदन का अधिवसन विना स्पीकर के हो ही नहीं सकता। 1943 ई म अप्यक्ष फिटजरो (Fitzroy) की मत्यू पर काम स समा का अधिवेशन यद्भकाल होत हुए भी तरत स्थिगत कर दिया गया था एव उनके उत्तराधिकारी के नियक्त होन के पश्चात ही सदन का अधिवनन हो। सका था। अध्यक्ष अवन पद से त्यासपत्र देकर प्रयक हो सकता है। सदन का सदस्य न रहते पर वह पद स स्वत हो प्रथक हो जाता है। अ सोवसभा को अध्यक्ष एव उपा-घ्यक्ष की पदच्यत हेन अपने स्वष्ट बहुमत स प्रस्ताव पारित करने का अधिकार है। 37 जन सदन एस प्रस्तान पर विचार विमय करता है तो उस समय वह सदन की अध्य-क्षता नहीं करता ।³⁸ लेकिन उस सदन म उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करन का अधिकार हाता है। अ लोकसमा के विषठित हो जाने पर स्पीकर अपने पद से प्रयक्त नहीं होता अपित नवीन निवाचनो क परचात नया स्पीकर निवाचित हान तक वह अपने पद पर बना रहता है।

शक्तियाँ--प्रिटिश कॉम स समा के स्पीकर की मौति बारतीय लोकसमा ने स्पीकर को निम्न व्यापन सक्तिया प्राप्त है

वह सदन की अध्यक्षता करता है। सदन म व्यवस्था एवं सांति स्थापित करता है। सदस्यों को याद विवाद म माय तेने की अनुमति देता है। सदन के नेता ए परामस स सदन के कायनम का निर्धारित करता है। सदन की सोर स नह स दसा की प्रहण करने एवं उन्हें भेजने की अनुमति प्रदान करता है तथा सदन का प्रीयत समस्त स दसा, अविदना, पत्रों आदि की वह स्वीकार करता है। यह नियमानुसार

³³ Article 93

³⁴ Article 93

Rule No 7 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, cited by M P Sharma The Government of Indian Republic 1972, p. 194

³⁶ Article 93 (a) and (b)

³⁷ Article 93 (c)

³⁸ Article 96 (1)

³⁹ Article 96 (2)

वाद विवाद की व्यवस्था करता है तथा औचित्य के प्रस्ता (Points of Order) को निरिचल करता है। वह प्रश्न एव प्रस्तावा को आमन्त्रित करता है तथा यह देखता है कि वे नियमानुसार ह अथवा नहीं। वाद-विवाद के दौरान वह अनावस्थक पुनरा बित्त को रोकता है। हुव्यवहार एव अनुसासन को माम करने वाले व्यक्तिया को दिण्डत करता है तथा वाद विवाद का समाप्त करना को मांग्र पर निष्य करता है। वह कवल स्वत में अधिकार एवं विशेषाधिकारों का ही रक्षक नहीं होना अपितु अल्पसस्यका के अधिकारों को भी मा यता देता है।

वह प्रस्तावा की आवश्यकता एव शीचित्य पर राष्ट्रीय हित की दृष्टि ते विचार करके उन्ह स्वीकृत या अस्वीकृत करन का अधिकार रखता है। वह मानी की

सदन के समक्ष सूचना प्रस्तुत करने क लिए कह सकता है।

वह गणपूर्ति क व्याव में सदन को स्थिमित कर सकता है। सदन म मतदान की स्थानस्था करके उसपे निर्णया की घोषणा करता है। सदन या उसके द्वारा स्थापित समस्त सिनित्या का वह सर्वोच्च अध्यक्ष है। वह समितिया के अध्यक्षा को सिनित्या पंत का चह सर्वोच्च का मान्या में निर्मय निर्मात है। सिनित्या के कार्यों की वह सुवना रराता है। कोई सिनित्य सन्ति कार्यों की वह सुवना रराता है। कोई सिनित्त सन्ति सम्बद्ध विना अध्यक्ष को अर्जुनति के अपना अधिवेशन नहीं कर सकती और राज्य या गानन के किनी अधिकार्य को अपने समक्ष उनकी पूब अनुप्रति के बिना गवाही देने के सिन् आपित्रात नहीं कर सकती है। काय रूप परामश्वादायों सिनित्त (Business Advisory Committee), नियम सिनित्र (Rules Committee) एवं सामा य वहेर्य सिनित्र (General Purpose Committee) का वह अध्यक्ष होगा है।

दोना सदना की संपुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसमा का अध्यक्ष ही करता है। ⁶⁰ वह धन विधेयका को प्रमाणित करता है। ⁶¹ वह सदन के बाद-विवाद म सामाय सदस्या की माति माग नहीं लेता और केवल निर्णायक मत ही देता है। सदन के सदस्यों की किताइया को सुनता है। लोकसमा का वह प्रमुख क्का ह। विशेष अवसरा पर वह सदन का प्रतिनिधित्व करता है तथा लोकसमा एवं राज्यसमा और लोकसमा एवं राप्ट्रपति के मध्य सम्पक्त का माध्यम है। उसका प्रमुख काय सदम म वाद विवाद एवं विवाद किया पर विवाद स्थाद करता है तथा लोकसमा एवं प्रमुख काय सदम्यक का माध्यम है। उसका प्रमुख काय सदम म वाद विवाद एवं विवाद किया विवाद का नोंड (Lord of Debates) की सजा दी जाती है।

स्थिति—कॉम स समा के स्थीकर की याँति वह सदन के सम्मान का सरसंक है। त्रिटिश स्थीकर की अनुकरणीय विशेषता, निष्यक्षता का अनुगमन करने का मारतीय स्थीकरों ने प्रयत्न किया है, लेकिन वं पूण निष्यक्षता के आदश को प्राप्त नहीं कर सके हैं। स्वत त्रता के पूब मारतीय के द्वीय धारासभा (The Ceatral Legislative

⁴⁰ Article 118 (4)

⁴¹ Article 110 (3)

Assembly) के अध्यक्ष थी विटठल माई पटेल अपनी यायत्रियता एव निप्पक्षता के . 1 निए विख्यात थे । ⁶² वे 1925 ई. में के द्रीय घारासमा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। बिटिश परम्परा के अनुस्प उहीने निर्वाचन के वाद अपने को निदलीय पापित किया या । 1930 ई म जब उ होने सिवनय बवता आ दोलन म माग तेने का निस्चय किया तो उहाने स्पीकर के पद से त्यागपत्र है दिया था । लेकिन विटिश निरपेक्ष निवलीयता का मारत म पूण अनुगमन नहीं हो सका है। वाबू पुरुषोत्तमहास टण्डन जत्तर प्रदेश विधान समा के यहास्वी स्पीकर थे। उद्दोने व्यक्तिगत आवरण म निर्भात निष्प क्षता का पालन किया था। परतु उहोन स्पष्ट शब्दो म यह भी कहा था कि इस वारा का भारत के लिए जिटेन का अनुगमन करना कठिन होगा। उनका मत या कि तन्त्र व म मारत् म ।वर्ष ।बटा मा यद्भाग मरता माना एगा। ज्याम पर माना अध्यक्ष की सदन के अंदर निर्द्धीयध्यक्ति के रूप य काय करना बाहिए पर वुसरन के बाहर सावजनिक जीवन में वह अपने दलीय सम्ब चा को नायम रख सकता है। ^{स्थ} स्वत प्र बाहर ताबकामक कावम न बह जनगवुणान चन्न चानगणाच्या पण्यादः राजाः न भारतीय मक्षराज्य के प्रथम लोकसमा के प्रथम अध्यक्ष भी मणक्ष वासुदव मावलकर भारताम भगराज्य भ नगम जामवाम भ जमम जामवा भा भम्म भावित्र माने जाते थे। वे वहे अनु-भवी एव प्रयान्ति प्रमावद्याती थे। श्री मावलकर की मायता थी कि मारतीय भवा ५७ भवान वामकारका मुक्त भवान प्रमाण प वह अपन दल का सदस्य रह सकता है लेकिन उस अध्यक्ष के रूप म अपन शावरण, ^{भेड़ जरा का भा अवस्य भेड़ अभवस्य हु भारत हु भारत का अवस्य भेड़ जिल्ला से काय करना चाहिए।}

7

बिदिश स्पीकर का निविरोध निविचन होता है। मावलकर ध की हिन्द म मारत क सावजनिक जीवन की वतमान अवस्था म विभिन्न राजनीतिक दला स इस अमितमय के पालन की बाधा करना कठिन हैं। माबतकर की इस धारणा म पर्याप्त बत है। अध्यक्ष का निविरोध निवाबित होना एवं उत्तवा निवतीय होना समान गी उत राजनीतिक विरावनता का प्रतीक है जा लोकत त्रीय व्यवस्था की प्रमुख वाधार-वत राजाराक महत्त्व है। फाइनर का यह कथन कट्ट सत्य है कि व्यवस्थारिय स प्रधान हर देस के राजनीतिक चरित्र का बिक्षाचीकरण (epitome) शुना ५ ।" नावतकर ने बिहिस स्पीकर को श्रादस माना या परन्तु मानलकर ने द्विट्स गर्भ भावतकर मा अधारण रमाकर मा जावन जामा चा मण्डु मानवा । अवस्ति स्वित् के मध्य के माम का अनुसरण किया है। स्वित् माक्कर अपन म व राजनीति सं पूणक्षण पुतकः नहीं रहे थे परन्तुं अध्यक्ष व हुन न अन्तर गाना निष्पक्ष रहा था।

ेश ना । अभी तक लाकसमा क पांच अध्यक्ष श्री गणेंग वागुटर = -१६४, जी उन्न विभा तर भागवना च भाग विभाव चा पण । वा पण

⁴² M N Kaul, cited by A C hapoor
M G Modern Governments Theory and A C Kapoor Indian Constitution, 1555 44 A C Kapoor op at, p 226

374 । जा गुनिक भासनतः त्र

 । मभो का प्रयाद्य सम्मान रहा है। अत्यक्ष र निषया स कभी-कभी कट्ट्रगापूष वाता वरण मा उपन हार है। एक बार ना मन 1954 ई म श्री मावनकर क विष्ठ एक विरोधी मन्स्य ने अविश्वाम का प्रम्तान भी उपस्थित कर दिया था यद्यपि नह पारित न हा मका। इम अविस्वाम का राज्या उनके विरद्ध तीत्र असताप था। उहींने तीन वप (1951 54 =) व बान म प्रस्ताविन ६९ बामराका प्रस्तावा म से कवल एक का ही स्वीकार किया था। अनक एम अवसर भी नोकसमा के जीवन म आप है जब कि स्पावन के विरोध में महत्व में जब्बवस्था का बातावरण पैदा ही गया और अन्यक्ष व आदेशा का उन्तपन किया गया तथा उसकी निज्यक्षता पर भाराप तगाव गय है। सन 1962 र में रेम प्रवार की घरना नोकसभा में हुई थी जिसम समाज वाली मन्द्रम भी राममवक यान्त का अध्यक्ष क आज्ञानसम्ब क अपराध म एक सप्ताह रें तिम मन्ते म निकासिन किया गया था।

कमी राज्या की विधानसमाजा क अध्यक्षा य विरुद्ध उत्तरदायी व्यक्तियो ने आपत्तिजनक विचार व्यक्त किय है। मितस्वर 1962 ई म उत्तर प्रदश् विधान ममा क एक अध्यक्ष न एक प्रन्तान पढा जिसम उत्तर प्रन्श के मुख्य मनी पर यह जारोप नगाया गया था कि मुख्य मात्री न यह कहा है कि अध्यक्त अपने की बुढिमान ममभता ३। उस यह जानना चाहित कि वह जो उँछ भी है वह भेरे अत्य कारण प्या है। वह विरोधों हेन भी इतना ममय हता है कि मुभ रुक्ता पहता है।' मुख म त्री क समा याचना करन पर ही मामला समाप्त हुआ था। " बिदिस स्पीकर को नित्पक्षता सम्बंधा ममी परम्पराठी का भारत म अभी विकास होना श्रप है। ब्रिटेन को माति मानतीय स्पीवर निविरोध नहीं चुना जाता। निविचना म उसका विरोध होता है और एक वार अ यक्ष वनने पर वह आजीवन अ यक्ष भी नहीं बना रहता है। नी मावनकर की म यु क बाद भी अन तरायनम आयगर 5 वप अध्यक्ष रहे थे। जनव वार सरमार हुकुमिनह अध्यक्ष बने । व भी कुछ वर्षों तक ही इस पद पर रहे । उनम पश्चात मजीव रडडी न स्पीकर का पद ग्रहण निया था । सारत म फ्रान्स को माति स्पीकर स सम्बर्धियत अवाद्यनीय "यवस्या का विकास हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। श्री अन तायनम आयगर गव सरवार हुकुमिंतह स्पीकर पद से मुक्त होन के बाद नमग्र विहान तथा राजस्थान राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किय गये। इसी प्रकार भी नीतम सजीव रहड़ी ने स्पीकर पद में त्यामपत्र देकर राष्ट्रपति पद के लिए निवाचन लड़ा था। ब्रिटिश स्पोकर अपने पद से या ता मत्यु के कारण ही हैटता है या पर सं हेटन पर सिक्य राजनीतिक जीवन से भी पृथक ही जाता है। भारत म स्पीकरो को गवनर जस किसी लाम के पद पर नियुक्त करना एक स्वस्थ 45 Gupta M G

⁴⁶ Gupta M G op cut P 499

परम्परा नहीं है। ऐसी स्थिति म उनसे पूणरूपेण निर्मीत एव निष्पक्ष होन की आधा करना कठिन हो जायेगा। राज्यों की विधानसमाओं के अध्यक्षा को स्थिति तो अमेरिकी एवं फेच स्थीकरों जसी हैं। अनेक ऐसे उदाहरण है जहां राज्य विधान समा के स्थीकरा ने मित्रपद ग्रहण करने के लिए त्यागपत्र दियं हैं। लोकत तीय विकास की हिष्ट से ये सव काय जन्जित हैं।

फिर भी घोरे घोर भारतीय स्पीकर निष्पक्षता एव निवलीयता के आदश की तरफ अग्रवर हो रहा है। माग कष्टसाध्य एव दुगम अवदय है लेकिन यह भी एक कटु सत्य है कि कोई व्यवस्थापिका सम्मान एव समतापुषक अपने दायिख को उस समय तक नहीं निमा सकती जब तक कि उसके अध्यक्ष की निष्पक्षता एव पायिप्रयता ने सदन को पूर्ण विद्यास नहीं।

विधि-निर्माण प्रकिया

विधि निर्माण प्रिन्या विभिन्न देखा मिन्न मिन्है। सामायत विधेयक के तीन वाचन होते हैं। तेकिन प्रक्रिया के विभिन्न स्तरो में अन्तर हाता है। सस्वीय एव अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले देखों की प्रतिया में भी जतर होता है। ग्रेट निर्देन, समुक्त राज्य अमेरिका एव भारत की विधि प्रक्रियाओं का अध्ययन अग्रिम पृष्टी में किया गया है।

प्रेट बिटेन की विधि निर्माण प्रक्रिया¹⁷

ग्रेट ग्निटेन में प्रस्तावित विभेयको क्षेत्र मुख्यत दो प्रकार—सावजनिक (Public) एव व्यक्तिगत (Private)—के विधेयको म वर्गीकृत किया जाता है। सावजिनक विधे यको का सम्ब घ सम्पूण देश एव जनता से होता है। उदाहरण के लिए निर्वावको की योग्यता म सर्शोपन सम्ब धी विधेयक सावजिनक विधेयक कहा जायया। व्यक्तिगत या जसावजिनक विधेयको का सम्ब च देशस्थानी समस्या सन हाकर किसी विधीय माग, वन या दित स होता है। किसी विशेष व्यक्ति, नियम, समुद्ध, समुदास, स्थानीय सस्य

Refer to Ogg and Zink Modern Foreign Governments pp 268 278 The British Parliament B I S Publication R5448/T3, May 1973 pp 19 25

⁴⁷ कनाडा, आस्ट्रेलिया एव यूजीलण्ड की विधि-निमाण प्रत्रिया पर ब्रिटिश प्रणाली का व्यापक प्रमाव है और उनम कोई विशेष जार नहीं है। कमाडा की कॉम स समा म ब्रिटेन की माित बहुमत दल का कठोर निय गण नहीं होता है। वाद-विवास अपेसाफ़त लम्बा होता है। 1913 ई म कनाडा म सम्पुट (closure) की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी थीं लेकिन उसका बहुत कम प्रयोग किया गया है। ननाडा की कॉम स समा म निश्चत कायनमानुसार बहुत कम काम होता है। सन के अतिम दिनों में सदन महत्वपूण मामलों का निपटान की जत्वी म रहता है। राजनीतिक दक्षों का कायकम मी ब्रिटेन की माित व्यापक नहीं होता और न ही दलीय अनुसासन कठार होता है।

या क्षत्र संसम्बन्धित विजेयक व्यक्तिगत विषेयका की श्रेणी में बाते हैं।उनका मामा य जनता में मम्बन्ध नहीं होता। व्यक्तिगत विषेयक सावजनिक विधयकों से

मावजिनक विश्वयन दो प्रकार के होते हैं— घन या वित्त विभेगक (Money Bills)। पन गर वित्तीय विजयक (Non Money Bills)। धन विभेगक (Money के हिन्नु जिन विधेगक का सम्बन्ध होता है। या त्रिमण्डल द्वारा समय के समक्ष स्वीकृति अपना है। या त्रिमण्डल द्वारा समय के समक्ष स्वीकृति प्रमान के जानी है तथा जिन विश्वयक को सदन के किसी अप सदस्य द्वारा समुक्त के व्यवित्तात सम्बन्ध को सदन के किसी अप सदस्य द्वारा स्व प्रकार जान है। वित्तीय एवं गर वित्तीय विश्वयक (Private Members Bills) के स्व त्र तर होता है। वित्तीय एवं गर वितीय विश्वयक्त के पारित करने की प्रणानी

गर वित्तीय सावजनिक विषयक निर्माण प्रक्रिया—गर वित्तीय सावजनिक विषयक का मनत्रथम किमी भी मदन लाडमभा या काम ससमा म प्रस्तुत किया जा मकता है। नोकत प्रत्यक विषयक का लावा सन्ता द्वारा पारित होता आवस्पक है। वि तयक क तीन वाचन (readings) होत है। इसके अविरिक्त द्वितीय एक पूर्तीय वाचन क मध्य की समिनि नवस्या एवं प्रतिवदन स्तर अय अवस्याएँ होती हैं। अव विधयर का प्राक्त मन्त्र म प्रथम एक वितीय वाचन मिनित स्तर, प्रतिवेदनस्तर, ात ततीय वाचन कुल नम म पाच अवस्थाओं म से हीकर गुजरना पडता है। कामस ममा म वि नवह क पानित होने पर उस हिनीय सबन लाहसमा म प्रस्तुत किया जाता है। नार्य समा मं भी विध्यक का इन पाच अवस्थाना मं स होकर पारित होना पडता है। विध्यम् का लाडममा स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है। यदि लॉडसमा द्वारा निषयक म महोपन प्रस्तावित किया जाता है तो वह पुनिवार हेतु काम स सना म वायम भन दिया जाता है। यदि वाम स समा द्वारा निरंतर हीन वाल दो समा म मार्गाम प्रमा श्री पार वर होन बाज प्रमा अर्थ प्रमा श्री कार्य के तही स्वाम और तहीय सन क मन्य की अविधि एक वेप से कम नहीं होती है तो विध्यक पारित माना बाता है तथा रामी/गजा क हस्ताक्षरा क निए भेज दिया जाता है। स्थापित परामरा अनुमार रानी/राजा निधेयक की अस्वीकार नहीं कर मकत ।

नाम समा म विधेयन को प्रस्तुत करन के पून भिमण्डल जन पर विचार विमान नरता है। विधेयन को प्रस्तुत करन को तर्मन के पून भिमण्डल जन पर विचार पिन सामा प बाता ना विनरण एक नाएन ने रूप म समसीय सलाहिकार। विधाय को जाता है। विशेष म समसीय सलाहिकार। (Parlia निर्मात बाता ना ध्यान म रस कर विध्ययन को तथाद करते हैं। वे पाएन म एव सम्बद्धिया स्वीकार करते के पून जम प्रमाणित कर दिया जाता है एव सम्बद्धिया स्वीकार किमण निर्माण का प्रमाणित कर दिया जाता है विधेयक का पारित करने की 5 अवस्थाओं का विवरण निम्नवत है

(1) प्रथम बाचन (First Reading)—विधेयक की सदन म प्रस्तुत करने की यह प्रथम अवस्था है। प्रस्तावक इस सम्बाध म दो में से एक रीति की अपना सकता है । प्रथम, प्रस्तावक अध्यक्ष को विधेयक प्रस्तुत करने की सूचना निश्चित प्रपन (Orders of the Day) पर प्रेपित करता है । निश्चित दिन सदन के अधिकारी-Clerk-द्वारा प्रस्तावक का नाम पुकारने पर वह विधयन की एक प्रति सदन की मेज पर रख दता है। द्वितीय रीति के अनुसार प्रस्तावक सदन म विधेयक प्रस्तुत करने के लिए समय की माग करता है। इस अवस्था म प्रस्तावक एव समयक क सक्षिप्त मापणा के पश्चात प्रस्ताव को अध्यक्ष द्वारा सदन के समक्ष मत हत प्रस्तत किया जाता है। सामा यत प्रथम माग का अनुसरण किया जाता है। प्रस्तावका के द्वारा प्रतीक विधेयक (Dummy Bills) इस समय प्रस्तुत किये जाते है। इस विधे-यक मे केवल विधेयक के शीपक का उल्लेख होता है, अय कोई विवरण नही होता। वास्तव मे पहले से ही तैयार एव सदन द्वारा स्वीकृत एक फाम होता है जिस पर विथे-यक का केवल नाम लिख दिया जाता है एवं सदन में प्रस्तुत कर दिया जाता है। प्रथम वाचन में कोई विवाद या वहस नहीं होती है। विधेयक (Bill) के सैयार हो जाने पर उसकी प्रतिया सदन के सदस्यों के मध्य वितरित कर दी जाती हैं। इसके पश्चात निध्चित तिथि को सदन म विधेयक का द्वितीय वाचन प्रारम्म होता है।

(2) द्वितीय वाचन (Second Reading)—विषयक को पारित होने की यह बहुत महत्वपूण अवस्था हु नयोकि हसी समय विषयक के सभी सिद्धान्ती पर विवाद एव विचार होता है तथा सदन के मत से उठे स्थीकृत या अस्तीकृत किया जाता है। प्रवृत्त निष्पा जाता है। प्रवृत्त निष्पा जाता है। प्रवृत्त निष्पा जाता है। प्रवृत्त निष्पा का स्वतिय वाचन होना चाहिए (The Bill be now read a second time)। वह विषयक के महत्व एव उद्देशों पर विस्तारपूषक प्रकाश डालता है। समयका द्वारा उसके समयन में तक दिय जाते हैं। विरोधी बता द्वारा उसकी आलोचना की जाती है जया विपरित स्थोगन का प्रस्ताव की एका जाता है, यथा—विषयक का 6 माह उपरान्त अपुन तिथि को द्वितीय वाचन हो। दूस प्रकार के प्रस्ताव का जय विषयक का अनिविचत का अतिविचत करने की भाग करना होता है। इसके पश्चात विषयक को अतिविचत का निष्पात करने होता है। विषयक के अस्वीकृत हो जाने पर रासन को

⁴⁹ The second reading is the most important stage through which the Bill is required to pass, for, its whole principle in their at issue and in affirmed or denied by a vote of the House "-Ers Line May Quoted by Herman Finer The Theory and Practice" Modern Government, 1956, p. 485

यागपन न्ना पड़ना है। लिनिन त्रम प्रवार की सामायत कोई आयका नहीं होती मयाकि मि त्रमण्डा बहमत त्त्र म म निमित्त होता है। द्वितीय बाचन के बाद विवाद ^{एव} विचार विमा व माय विधयन पर गारावार वहस नहीं हाती। द्वितीय वाचन का उहेड्य विषयम म मिद्वाना भी स्वीमित हैना है।

द्विनीय वाचन ∓ लौरान वा मिमिनि-स्तर एव प्रतिवदन-स्तर होत हैं।

()। सिमिति स्तर (The Committee Stage)—सावजनिक विषयक द्वितीय वाचन र लागन म मन्या धन स्वायी मिनिन (Standing Committee) को भेव दिया जाता है। तेहिन यि का मन्य विवयक का सम्पूण सदन की समिति (Com mittee of the Whole House) या किसी प्रतर समिति (Select Committee) म भजन का प्रस्ताप करना ह ना व सन्न र निषय के अनुसार उक्त समिति की भेज नियं जान है। सामा यन यह बपूण विषय सम्पूज सन्त की समिति (Committee of the Whole House) म प्रियन निय जाते हैं। प्रवर समिति म किसी विश्वयक का विशय अउस्था म ही भेजा जाना है।

मिति स्तर म विध्यक पर वारावार विचार होता है। संशोधन प्रस्तावित किय जात है एवं नवीत घागाँ जाड़ी जाती है। हर बारा को पुषक वे समिति को मगानित तब स्नीकृत या जस्बीकृत करने का अधिकार होता है। सामान्यव समिति म सयत बान विवाद होता है। सदस्यगण मिनिति म एक प्रन्त या विवय पर अनेक बार बात सबत है। यदि बिरोधी दल बाहै ती प्रत्येक घारा पर सतदान की माम मी कर सकता ह।

गामकोय विधयक का पारित कराने का वायित्व किसी न किमी मनी का होता है। उसका यह निविश्व ह कि विधयक म एसा काइ ससोधन ने किया जाय जिसम विरेयक के सूत्र मिद्धा तो में परिवतन ही जाय। समिति में चूकि सत्तास्त दत का बहुमत होता है अत विश्वयंक म संशोधन सम्बंधी एस किसी प्रस्ताव की स्वीकार नहीं किया जाता जिसस उसक उद्देश्या म अंतर पड़ता हो ।

(4) प्रतिवेदम स्तर (Report Stage)—सिमिति का अध्यक्ष विधयक पर विचार विमन्न होत के परचात सबन को विषयक को गैटाते हुए प्रतिवेदन देता है। प्रतिबदन म प्रस्तावित संशाबन पर सदन म बहस हाती है। वस स्पिक संशोधन प्रस्ता विन किय जात है। इस अवसर का गासन द्वारा नाम उठाया जाता है और उन ममत्त संवाधना को जिह धासन सिद्धा तत पहले ही स्वीकार कर चुका हो एव जिनक अनुरूप विध्यक म संशोधन का वचन दिया ही और जो संशोधन किही भारणो में मामिति स्तर पर नहीं किय जा सक व स्वीकार कर लता है। यदि विधयक पर सम्ब्रण सदन की समिति म विचार होता ह तो प्रतिवदन दन की कोई आवस्यकता ही नहीं होती।

ए.... . (5) ततीय नाचन (Thud Reading)—प्रतिवदन क पश्चात विषेयक सदन

Fa. वीर 0_{rd_i} 神 प समक्ष तृतीय याचन के हुतु प्रस्तुत निया जाता हु। यह निसी सदन म विषेयर मी जित्तम अवस्था होती है। इस अवस्था में विषेयर में चवल मौग्मिक एवं मापा सम्बन्धी संगोधन ही प्रस्तावित नियं जा सचते है। यविष ज्ञदन विषेयक ना स्वीमार या अस्थी-मार कर सम्बत्त है परानु इस अवस्था में आकर सामायत नाई विषेयक अस्थी हत नहीं होता। ततीय वाचन में विषयक पर विचार विमय एवं वाद विवाद होता है। समरणीय है नि सदन द्वारा विषयक ने सिद्धा तो मों द्वितीय वाचन म अस्थीचार गर चूनन क परचात उस पर तिवित मं विचार विचार होता है। अत ब्रितम स्थी कृति करने के पूर्व समा एक यार पुन निरीक्षण आवश्यन होता है। यहां ततीय ताचन का उद्देश्य है। यहां तरा प्रमुत्त तिरीक्षण आवश्यन होता है। वहां ततीय तो वाचन का उद्देश्य है।

इ ही पीचा अवस्थाओं में से होकर विषेयक को लॉडसमा मस गुजरना पडता है एवं द्वितीय मदन द्वारा स्वीकृत होने पर राजा या रानी के समक्ष विषेयक हस्ता-क्षरा ने लिए प्रस्तुत निया जाता है एवं उनके हस्ताक्षर होने पर विषेयक पारित माना जाता है एवं विषिय वन जाता है।

व्यक्तिगत विधेयक (Private Bills)-सार्वजनिक विधेयका स व्यक्तिगत विधेयका को पारित करन की पद्धति भिन है। इनलैण्ड म प्रति वप बहुत से व्यक्तिगत विभेयक पारित किय जात हैं। इनम स अधिवादा विभेयका द्वारा स्थानीय संस्थाजा को विरोप शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। स्मरणीय है कि व्यक्तियत विधेयका के प्रस्ता वक ससद सदस्य नहीं हात अपित् व ससद के बाहर के व्यक्ति या निकाय होते है। सामा यत विधेयक इनकी तरफ स ससदीय अभिकर्ताओ (Parliamentary Acents) द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार के विधेयको को एक प्राथनापत्र (petition) के साथ सलग्न वरके आवदन के रूप म प्रस्तुत किया जाता है। इसके पश्चात प्रस्ता-वित विधेयक को समद व' दो व्यक्तिगत विधेयका के परीक्षका (Examiners of Petition of Private Bills) क पास निरीक्षण हेतु भेज दिया जाता है। इस प्रशार के विधेयक को प्रस्तावित करन के पुत्र उसस सम्बन्धित व्यक्तिया को लिखित रूप में सुचित किया जाता है जिसस कि उन्ह विधयन की सूचना हो सके। प्रस्तावित विधेयक की अग्रिम प्रतियां सम्याधित विमागो का भी भेजी जाती है। परीक्षका का दायित्व यह है कि वे देखे कि सम्बाधित हिता एव विभागा का सूचित किया जाता है और विधेयक की प्रतियाँ उन्ह भेजी जा चुकी है। सभी औपचारिकताजा के पूण होने पर वे विधेयक को प्रमाणित (certify) करते है एव इसके पश्चात ही विधेयक किसी सदन मे प्रस्ता-वित विया जा सकता है। यदि सभी औपचारिकताएँ पूण नहीं होती तो परीक्षका के द्वारा विधेयक दोना सदना की स्यायी जादेशो की समिति (Committee of Standing Orders) को भेज जात हैं। इस समिति को औपचारिक अपूषता की उपेक्षा करन सम्ब धी निणय कर सकने का अधिकार होता है।

सदन म व्यक्तिगत विधेयक के प्रस्तुत किय जान के पश्चात उसका प्रथम

दितीय वाचन सावजनिक विवेयकों की माति ही होता है। प्रथम वाचन म सदन म विवेयक का केवल श्रीपक पढा जाता है। द्वितीय वाचन मे यदि विवेयक का विरोध नहीं होना तो उस निविदांच विवेयक समिति (Committee of Unopposed Bills) को भेजा जाता है। यदि विवेयक का विदांच किया जाता है तो उसे व्यक्तिगत विभ यक समिति (Private Bill Committee) को भेजा जाता है। इस समिति म कॉम स समा के 4 एव लॉडसमा के 5 मदस्य होते हैं। इस समिति के सन्दर्यण विवेयक से विमी प्रकार मी सम्बीचित नहीं होते। कमी-कमी बहुत से व्यक्तिगत विषेयकों को एक ही समिति में भेज दिया जाता है।

सिनित म विषेयक पर मायालयों की माति ही विचार किया जाता है।
मवप्रथम सिनित मे विषेयक के उद्देशों एवं प्रयोजनों पर विचार होना है। इतक
पदचात विषेयक के उप्देशों एवं प्रयोजनों पर विचार होना है। इतक
पदचात विषेयक के प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के पक्ष एवं विपक्ष में वयान विय
जाते हैं। सम्बच्चित व्यक्तियों को तमिति में अपना एक्ष प्रम्तुत करने के लिए विषक्ति
नियुक्त करने की मुविधा प्राप्त होती है। यदि समिति विधेयक के उद्देश एवं प्रयोजन
का उचित मान नेनी है तो विधेयक पर लागे घारावार विचार प्रारम्भ होता है।
मम्बित वासकीय विभाग के प्रतिवेदन पर सी माय साथ विचार किया जाता है।
समिति द्वारा विचार किये जाने पर विधेयक को अपने निषय सिहत वह सवन को शोटा
देती है। नामायत समिति के प्रतिवेदन को सदन द्वारा स्वीकार कर तिया जाता है।
यदि समिति म विधेयक के विच्द निजय होता है ता सदन उसे अस्वीकृत कर सम्बाह
अथा ततीय वाचन होता है। एक सदन म विधेयक के परित्र होन कं परचार वह
स्वी रीनि से द्वितीय सदन म भी पारित किया जाता है और सम्नाद की स्वीकृति के
परचात विधि वन जाता है।

तिरन म व्यक्तिगत विद्येयका पर राजनीतिक दलव दी की हृद्धि संविचार नहीं किया जाता है । इन विधेयका का पारित होना उनकी उपयोगिता पर निमर करता है। ये विदेयक सदन क अविवादसस्त (non controversial) काय माने जाते हैं एवं एक सदन म विधेयक क पारित होने पर उसे दूसरा मदन सरसता से स्वीकार कर सेता है।

स्पानीय सस्याओं को सदन से अधिकार-वृद्धि के लिए आवेदन के अधिकार दकर निश्चित क्य से एक कभी को पूरा किया गया है। परिवृत्तित परिस्थितिया म नवीन अधिकारों को आवरयकता हा सबती है। होती, वडी, नियम एव सम्पन्न सभी सस्याओं का इस सुविधा के कारण समान विधियों के अधीव काय नहीं करना पडता है। इसर अितरिक्त स्थानीय सम्याओं को इस वात की प्रविद्धा भी नहीं बरनी पडती कि समर्थ स्वा अवस्थक विधि को निर्माण कर । सस्याएँ स्वय प्रस्ताव नरने आवस्यन विधि क निर्माण कर । सस्याएँ स्वय प्रस्ताव नरने आवस्यन विधि क निर्माण कर । सस्याएँ स्वय प्रस्ताव नरने आवस्यन विधि क विष् पहल नर सकती हैं। लेकिन क्योंसिमन विधियका की पारित करने म बहुत अधिक समय एवं धन क्या होता है।

गर सरकारी विषेयक (Non Government Bills)—इ ह व्यक्तिगत सदस्य विषेयक (Private Members Bill) भी कहते हैं। यह मी सावजनिक विषेयक होते हं, अत्तर केवल इतना होता है कि ये किसी मात्री द्वारा प्रस्तुत न करके किसी साधा-रण सदस्य द्वारा प्रस्तावित किये जाते हैं। कॉम स समा का अधिकाश समय शासकीय काम-काज में ही व्यतीत हो जाता है। वर्त गैर सरकारी विषेयको पर सप्ताह में केवल शुनवार के दिन ही विचार होता है एव एक सन में इनकी अधिक से अधिक सक्या 20 हो पाती है। इसके अदिरक्त एक शुनवार विषेयको के लिए, तो दूसरा मुक्तार प्रस्तावो आदि के लिए निश्चित होता है। अत एक सन म केवल 10 दिन ही गैर सरकारी विषेयको पर विचार विमयहें प्राप्त हो सकते हैं। यह समय पर्याप्तत कम है एव समस्त गैर-सरकारी विषयको पर विचार विमयहें प्राप्त हो सकता सम्भव नहीं होता है। अत तन के प्रारम्भ में हो विषयको पर विचार ताता है एव क्षत्रार नाम निकलने पर सुची को अवविस्त कर निवार जाता है एव क्षत्रार नाम निकलने पर सुची को अवविस्त कर निवार जाता है एव कुकवार को कम में उ ह वियोग को प्रस्तुत करने को आमिनत किया जाता है। निचारित कुकवारों की सख्या समाप्त होने पर जो विषयक रह जाता हो, विचारित कुकवारों की सख्या समाप्त होने पर जो विषयक रह जाता है, उनको कोई अवसर प्राप्त नहीं होता।

गैर सरकारी विधेयक को खासकीय सहानुभूति के अमाव मे पारित होना सम्मव नहीं है। यदि शासन ना पूज समयन न हो तो कम से कम यह तो आवश्यक है ही कि उसे कम से कम निरोध को सामना करना पढ़े। मिन्नमण्डल द्वारा निरोध किये जाने पर निष्येयक का प्रयम नाचन में ही अत हो जाता है यदि मिन्नमण्डल के निरोध के पश्चान मी कोई गैर सरकारी निष्येयन पारित होता है तो इसका यह अय है कि मी नमण्डल में सदस्त को अविश्वास है। ये विषयक मी सरकारी निष्येयकों की माति पूषक पूषक दोना सदमा द्वारा तीन वाचनों म पारित किये जाते हैं एवं सम्माद की स्वीकृति प्राप्त करके विधि वनते हैं।

ब्रिटिश विस व्यवस्था⁵⁰

त्रिटिश ससद—व्यवहार म कॉम स समा—राष्ट्र क वित्त पर निय त्रण रखती है। राष्ट्रीय वित्त का प्रवाध ससद का सबसे अधिक महत्वपूर्ण दाथित्व है। जिसका वित्त पर अधिकार होता है वही सत्ता पर अधिकार रखता है। आधिक निय त्रण के माध्यम से शासन पर निय त्रण रखा जाता है। ब्रिटेन म वित्त पर ससदीय निय त्रण के निम्न वार प्रकार है —

- (1) शासनीय विभागा एव उनके कार्यों के लिए आवश्यक अनुदाना को स्वी-कृत करना।
 - (2) शासनीय वाय के साधनी—करो—को निर्धारित करना ।

⁵⁰ Refer to Ogg and Zink op at, Chap MIII, pp 279 294, Finer, H op at, pp 508 512

- (३) स्वीकृत अनुदाना कं त्यय का निरोक्षण एवं समीक्षा ।
- (4) ज्ञामकीय नाय एव व्यय का नम्त्रा पराक्षण।

. मावजनिक जित्त व्यवस्था न सम्ब ज म पहले शासन के अनुमानित व्यय की निधारित रिया जाता = एवं तत्रनुरूप आय की व्यवस्था की जाती है ।स्मरणीय है कि वित विध्यकों को सवप्रयम काम स समा म ही प्रस्तृत किया जाता है। साउत्तरा को अभिन स अभिन च है गन माह तर राकन का अधिकार प्राप्त होता है। यदि लाड समा राम स समा क प्रस्तावित मुक्तानों को स्वीकार नहीं करती तो काम स सभा जिस रूप म वित वि स्यक् पारित करती है उसी रूप में वह पारित माना जाता है। वित वि स्वर को स्पीकर प्रमाणित करना है एवं इस सम्बंध में उसका निणय अतिम होना है। विल विधेयका की पारित हान को पद्धति गर विलीय विधेयको से सिन होती 🤣 । ग्रंट न्निटेन व आय व्यय प्रपत्र (Budget) में अब दा-विनियोग एवं राजस्व---विधयका (Appropriation Act and Finance Act) स है जो पृथव-पृथक रूप स काम संसमा पारित वरनी है। पहले वाधिक व्यथा के जनुमाना (Estimates) की काम स समा म जनवरी क अतिम या फरवरी के प्रथम सप्ताह में वित्त-मात्री द्वीरा प्रस्तृत किया जाता है। अनुमानो क प्रस्तृत करन क पडचात विस्त विधयक या राजस्य वि अयर को जिसका मन्बाध कर प्रस्तावों स हाता है सन्त स प्रस्तुत किया जाता है। विन म नी (Chancellor of Exchequer) जिस दिन बजट का कामस समा म प्रम्तुत रनता हे वह रिन उबट दिवस' (Budget day) बहलाता है । वित्तमापी हारा इम त्नि मापण त्या जाना है। इम मापण हारा आगमी करो का पता बल नाता है। विनियाम वि स्वक नो विभि न विभागा न सहयोग स विस्त विभाग 67 माहम तयार रण्ता है। दोनां वि यको पर विचार विमण के लिए काम से सम अपने को पूर्ण सन्त की लिमिनि (Committee of the Whole House) में परिर्वातन कर रेती है। निनियाम विश्वक पर विचार करने समय काय स समा की सम्पूर्ण मिनि का पूर्वि समिति (Committee of Suppls) की सना दी जाती है और जब काम समा राजस्व वि । यक पर विचार विमा करती है तो उसे उपाय एवं साधत समिति (Committee of Wass and Means) कहत ह । राजस्व या कर सम्ब सी प्रस्तावा का उपस्थित करत समय पृथ गापनीयता वरती जाती है और संदर्ज में प्रस्तुत ररतं व पूर्व यति उसका काई अस प्रकाशित हा जाता है तो वह वित्त मापी मो लयाग्यता का प्रमाण माना जाता है। फनस्वरूप विन मंत्री को त्यागपत्र देना

व्यय न सम्पूष अनुमानां पर बाद बिगाद एव निषय हुतु इवल 26 दिन निपारित होत है। प्रत्यक बिजाय के लिए समय निविश्त हाता है और इस अविषि स पदि सम्बर्धित विचाय की सम्पूष सौंधा पर विचार विसर नहीं हो पाता तो सम्पुट (closure) का प्रयास किया जाता है। बहुस प्रभू स होकर चार-मींब महीना म बिखरी होती है अन फरवरी से जुनाई तक वजट पर वहस होती रहती है। स्मरणीय है कि वजट की अवधि प्रति वप 31 माच को समाप्त हो जाती है और नवीन वितीय वप 1 अप्रल से प्रारम्म होता है। बहुषा बजट की स्वीकृति इस तारीख तक नहीं हो पाती है। अत पूर्ति समिति (Committee of Supply) पहली अप्रल ने पूर्व ही कुछ महोनों के व्यय हुंत आवश्यक पनराधि को अधिम स्वीकृति दे देती है। इसे अप्रिम स्वीकृति (Vote of Account) कहते है। यदि यह घनराधि कम पडती है और निर्मारित अवधि म बजट स्वीकृत वही हो पाता है तो पुन अतिम 'अप्रिम स्वीकृति प्रारम की जाती है।

कॉम स समा म प्रस्तावित व्ययो में साधारण सदस्यों को केवल कमी या कटौती का ही प्रस्ताव करने का अधिकार होता है। वे व्यय की नयी मदों की बृद्धि का प्रस्ताव नहीं कर सकते। ब्रिटिश वित्तीय व्यवस्था के अनुसार सिद्धात्तत व्यय की माग तो सम्राट के नाम पर मित्रयों द्वारा ही की जा सकती है। साधारण सदस्य न तो करारोपण की नाम कर सकते हैं और न उनकी बद्धि का प्रस्ताव कर सकते हैं। वे व्यय की मागों या करों के प्रस्ताव म केवल किकायत, कटौती या कमी का प्रस्ताव कर सकते हैं

अप के अनुमाना एव कर प्रस्तावो पर जब सदन कमश पूर्ति समिति (Committee of Supply) तथा उपाय एव सावन समिति (Committee of Ways and Means) के रूप में विचार विमय रूप कुरता है तो वे कॉम स समा वे पास भेज दिये जाते है । इस दो विधेयका के रूप म सगठित किया जाता है। क्यय प्रस्तावा सम्बाधी विधेयक को 'वितियोग विधेयक' (Appropriation Bill) एव कर-प्रस्तावा सम्बाधी विधेयक को विस्त अथवा राजस्व विधेयक (Finance or Revenue Bill) कहते हैं। ये दोता विधेयक स्पृत्त रूप से देता विधेयक समुक्त रूप से बजट (Budget) कहे जाते हैं। अत विधेयकों को मौति इसे मी तीन वाचना में पारित किया जाता हैं पर शु अय विधेयका की माति इस पर विशेय जावन के स्तर पर समितिया म विचार नहीं होता यथोकि कॉम स समा की दो प्रणासदन सिमित्य इस पर पहलिया म विचार कर चकती है।

सयुक्त राज्य अमेरिका की विधि-निर्माण प्रक्रिया 1

सपुक्त राज्य जमेरिका की विधि प्रणाली कुछ जर्यां में बिटन से मिन्न ह । न्निटेन की तरह सपुक्त राज्य अमेरिका म विधेयक तीन प्रकार के नहीं होते । अमेरिका म सावजनिक विधेयका (Public Bills) से अथ उन विधेयका से हैं जो मौलिक महत्व के होते हैं एवं महत्वपूष आयकीय नीति स सम्बन्धित होते हूं। व्यक्तिगत विधेयका (Private Bills) ना सम्बन्ध गर-सरकारी एवं व्यक्तिगत मामला स होता है। इगलज्ड

⁵¹ Refer to Ogg and Ray The Foundations of Government in the United States 9th edn, pp 210 230 Harold Zink, H R, Penniman and G Il Hawthorn American Government and Politics, 1967, pp 180 206

(3) म्बोङ्कत अनुदाना 💤 २य का निरीक्षण एव समीक्षा ।

(4) गामकीय जाय एवं व्यय का लेखा परीक्षण । मावजितक वित्तं यवस्या व मध्य घम पहल शासन क अनुमानित व्यव हो निधारित विया जाता ह एवं तत्नुम्प वाय की व्यवस्था की जाती है ।स्मरणीय 🛊 वि वित्त विश्वयका को मवयथम काम म समा म ही प्रस्तुत किया जाता है। नाइतमा का अधिव म अभिक उन्हान मान तक रोकन का अधिकार प्राप्त होता है। यदि लाह मसा काम म समा क प्रस्तावित मुभावा को स्वीकार नहीं करती तो कामस समा विस रूप म बिल वि ।यक पानित करता है उसी रूप म बह पारित माना जाता है। बित वि स्पन का स्वाक्त प्रमाणित करता है एवं इस सम्बन्ध में उसका निषय अतिम होता ै। जिल नि गयका की पारित होने की पढ़ित गर विलीय विधेयका से मिन होती है। यह विकत के आय त्रवह (Budget) में अथ ही—विनियोग एवं राजस्व— वि त्यका (Appropriation Act and Finance Act) स है जो दूपर वृषक रूप म रोम म ममा पाणिन करनी है। पहने वाधिक व्यथा के जीमाना (Estimates) की राम म गमा म जनगरी र अनिम या फरवरी क प्रथम सप्ताह म बितन्त्री हारा प्रस्तृत हिया जाता = । अनुमाना क प्रस्तृत करत क पश्चात विश्व विश्ववह या राजस्य वि । उर का जिसका सम्बन्ध कर प्रस्तावा स होता है सदस म प्रस्तुत हिया बाता है। विल म त्री (Chancellor of Exchequer) जिस न्नि वजट की कामस समाम प्रमान रहता पर हिन राजर हिनस (Budget day) बहताता है। वितासकी होरा >म जिल्लामायण जिल्ला काता के कियाबुद्ध प्रथम) वह पता ए जाना के। विनियाम निरमक की विभिन्न विभागा के सम्योग से बित्त विभाग 67 मात्र म नवार करना का काला न विचार विचार विचार के निव्य कामस समा नपन का प्रण मन्त्र का मिनित (Committee of the Whole House) म परिवर्तित रर तनी है। तिनित्राम विश्वस्त पर विश्वास करण समय काम स समा की समूल मिनि का दिन मिनि (Committee of Supply) की महा दी जाती है और उब होमण ममा राजस्य विश्वस पर विचार विधान रहती है मो उस उपाय एवं सापन मिनिन (Committee of Wass and Means) रहन है। राजस्य या नर सम्बरी प्रध्याचा च । उपित्रात कुन समय पूर्ण सावनीयता चर्गी जाती है और मन्त्र स वस्त्र राज र पृष्ठ विक्र अस्त्र राष्ट्र जा प्रकारित हो जाता है तो उह विक्र प्राप्त को अपाध्यमा को प्रमाण माना जाना के। जनस्वक्य जिन मंत्री को स्वामण्य त्या 45.41 2 1

ध्यत् क मामून अनुमाना पर बाल विशाल एवं विषयं हें वे प्रत 26 निव रिधारित होत् । व उन विमान न तिम समय तिन्धित शीता है और इस अमीप ने वर्ष- मन्त्री पत्र किनाव को मन्त्रूच सीवा पर विभाग मि । मही ही बाम भी सन्त्रूच (cl nure) का प्रवास किया आसा है। बहुन प्रमान ने हाक्ट सहनी ह महीना ब

विखरी होती हैं अत फरवरी से जुलाई तक वजट पर वहस होती रहती है। स्मरणीय है कि वजट की अविध प्रति वप 31 माच को समाप्त हो जाती है और नवीन विस्तीय वप 1 अप्रैल से प्रारम्भ होता है। बहुधा बजट की स्वीकृति इस तारीख तक नहीं हो पाती है। अत पूर्ति समिति (Committee of Supply) पहली अप्रल ने पूर्व हो कुछ महीनों के ध्यय हेतु आवश्यक धनराशि को अग्रिम स्वीकृति दे देती है। इस अग्रिम स्वीकृति (Vote of Account) कहते हैं। यदि यह घनराशि कम पडती है और निवारित अविध म वजट स्वीकृत नहीं हो पाता है तो पुन अतिम अग्रिम स्वीकृति' प्रारत की जाती है।

काम स समा में प्रस्तावित व्यया म साधारण सदस्यों को केवल कमी या कटीती का ही प्रस्ताव करने का अधिकार होता है। वे व्यय की नयी मदा की वृद्धि का प्रस्ताव नहीं कर सकते । विटिश वित्तीय व्यवस्था के अनुसार सिद्धात्तत व्यय की मान तो सम्राट के नाम पर मिनया द्वारा ही की आ सकती है। साधारण सदस्य न तो करारोपण की मान कर सकते हैं और न उनकी वृद्धि का प्रस्ताव कर सकते हैं। वे व्यय की माना या करा के प्रस्ताव म केवल कि कायत, कटीती या कमी का प्रस्ताव कर सकते हैं

क्यम के अनुमाना एव कर-प्रस्तावा पर जब सदन कमश पूर्ति समिति (Committee of Supply) तथा उपाय एव सानन समिति (Committee of Ways and Means) के रूप में विचार विमश्न कर चुकता है तो वे कॉम्म स समा के पास भेज दिये जाते हैं। इ ह वा विधेयक के रूप म समिठत किया जाता है। क्यप प्रस्तावा सम्ब भी विधेयक को 'विनियोग विधेयक' (Appropriation Bill) एवं कर प्रस्तावों सम्ब भी विधेयक को 'विनियोग विधेयक' (Appropriation Bill) एवं कर प्रस्तावों सम्ब भी विधेयक को विस्त अथवा राजस्व विधेयक (Finance or Revenue Bill) कहते हैं। ये दोना विधेयक समुक्त रूप से बजट (Budget) कहे जाते हैं। यत विधेयकों की माति इसे पर हिती वाचना म पारित किया जाता है पर तु अप विधेयकों को माति इस पर दित्रीय वाचन के स्तर पर समितियों म विचार नहीं होता वयांक कॉम'स समा की दो पूण सदन समितिया इस पर पहले ही विचार कर चुकती है।

सयुक्त राज्य अमेरिका की विधि-निर्माण प्रक्रियां

सपुक्त राज्य अमेरिका की विधि प्रणाली कुछ वर्षों में ब्रिटन से भिन्न है। ब्रिटेन की तरह सपुक्त राज्य अमेरिका में विधेयक तीन प्रकार के नहीं होते । अमेरिका में सावजनिक विधेयको (Public Bills) स व्यय उन विषेयको से हैं जो मौतिक महत्व के होते हैं एव महत्वपूर्ण शासकीय नीति से सम्बन्धित होते हैं। व्यक्तिगत विधेयको (Private Bills) का सम्बन्ध म गर-सरकारो एवं व्यक्तिगत नामको स होता है। इगलैण्ड

⁵¹ Refer to Ogg and Ray The Foundations of Government in the United States, 9th edn pp 210 230 Harold Zink H R, Penniman and G B Hawthorn American Government and Politics, 1967, pp 189-206

384 | बाघुनिक शासनतन्त्र

के वर्षों म यहा सावजनिक विवयक नहीं होते । इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य वर्गाका म विधेयका (Bills) एवं संयुक्त प्रस्तावो (Joint Resolutions) म भी अंतरहोता है यद्यपि दोनो म कोई विशेष अतर नहीं है। विभेषका की अपेक्षा संयुक्त प्रस्तावा का अन सकीण होता है एवं उनके उद्देश्य भी स्थायी होत है। सदन म कायवारी प्रस्ताव (concurrent resolutions) भी प्रस्ताचित किये जाते हैं। इन्हें सरस सदन (Sim ple House) या सीनेट के प्रस्ताव भी कहा जाता है। ये सरस प्रस्ताव सदनो कविचार ाव हिटकोणों को ध्यक्त करत है और इह राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए ही भेजा जाता है। इनका कोई विधिक महत्व भी नहीं है। स्मरणीयहै कि सावजनिक एव व्यक्तिगत विधेयको तया संयुक्त प्रस्तावा के मध्य भेद को व्यवहार म मायता नहीं शे जाती है। तयुक्त राज्य अमेरिका में सभी विधेयक व्यक्तियत सदस्या द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं। इसका कारण शक्ति पृथक्करण के सिंहा त पर आधारित अध्यक्षात्मक गामन ह्यवस्था है। कायपालिका व्यवस्थापिका का अस नहीं होती है और न वह उसके प्रति उत्तरदायो ही है। त्रिटिश विधि निर्माण प्रक्रिया का अमरिकी पढ़ति पर सपट प्रमाव है। उवाहरणाय-विधेयक क्षेत्रों सदनो द्वारा तीन वाबनो म पारित किर जाते हैं सिमिति यनस्या दोनो देशो म है पर तु दोना देशा म निस्तार की बातो म पर्यान भतर पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका म विधेयक को निम्न अवस्थाओं म स होकर पारित होना पडता है (1) विध्यको का आरम्म (Introduction of the Bills) एव प्रथम वाचन (First Reading), (2) समितिन्तर (Committee Stage), (3) मूची-स्तर (Calendar Stage) (4) दितीय वाचन (Second Reading) एव (5) ततीय बाचन (Third Reading) । इनका बिस्तृत विवरण निम्नवत है

(1) विधेयक का आरम्भ एव प्रथम वाचन-अमेरिका म विधयको को प्रस्तावित करना बहुत सरल है। समस्त गैर वितीय विधेयक काग्रेस क किसी सदन में प्रथम बार प्रस्तावित किय जा सकते हैं। वित्त विधेयक प्रथम बार प्रथम सदन-प्रति निधि सदत-म ही प्रस्तुत किय जाते हैं। प्रस्तावक विध्यक की एक हस्ताक्षर युक्त प्रति प्रतिनिधि सदम के नतक (Clerk) या चीनट म संनेटरी (Secretary) नी मन पर रखी एक वेटी (hopper) म हाल देता है। विधेयक की प्रस्तुत करने की क्रिया

प्रण हो जाती है। बीग्रस क प्रत्यक सत्र म हजारा की सक्या म विषयक प्रस्तावित किये जात है। प्रत्यक मदस्य का जनक विधेयक प्रस्तावित करने का अधिकार होता है। प्रस्तावित विधेयक्। की कमानुसार संस्था प्रदान की जाती है। इस प्रकार विधयक को प्रस्तावित करना—प्रथम वाचन—पुष हो जाता है। यह नेवल औपचारिक मात्र है।

(2) समिति स्तर (Committee Stage)—इसके परचात विषेयक नवक द्वारा सम्यो धत समिति क पास भेज दिया जाता है। विषेयक नो निस समिति के पास भेना जाय जेती कोई गुना उत्पन्न व्याप्त है। १९५५क १। ११ व पाणाव र राज्या होने पर सदन के अध्यक्ष का निषय इस सम्बद्ध म भा भाग पहा भार 191 अभाव हात पर प्रथम प प्रथम भाग प्रथम अभाव होता है। समिति में विधेयक की प्रारम्भिक जीव के प्रचात जसारी महत्वपूर्ण

? È 19 * 57 एव आवश्यक समभने पर विधेयक पर आगे विचार विमश होता है अयथा विधेयक का अत हो जाता है। अनावश्यक विघेयको को दफ्तर-दाखिल (file) कर दिया जाता है। इसे ही विधेयका की अकाल मत्यु (pigeon holed) कहते हैं। समिति म विधे-यक पर बाराबार विचार होता है। सम्बन्धित व्यक्तियों के विचारों की सूना जाता है। समिति को विधेयक म सशोधन एव आमूलचूल परिवतन करने तक का अधिकार होता है. वह शीपक को छोडकर शेप विधेयक को प्रणरूपेण परिवर्तित कर सकती है। वह विथेयक को अस्वीकृत भी कर सकती हैं। ग्रेट ब्रिटेन की तरह यह आवश्यक नहीं है कि मिनितियां प्रत्येक विधेयक को अपने प्रतिवेदन सहित सदन को वापस करे। जिन विधेयको को वे अस्वीकार कर देती है, उन पर वे प्रतिवेदन ही नहीं देती और वह विधेयक समिति अवस्था मे ही समाप्त हो जाता है। स्मरणीय है कि प्रतिनिधि सदन अपने सदस्यों के स्पष्ट बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधेयक को स्वय विचार करने के लिए समिति से वापस में गा सकता है। सीनेट भी प्रस्ताव पारित करके समिति को विधेयक पर विचार करने से रोक सकती है एव विधेयक पर स्वय विचार कर सकती है। समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रतिवेदन दिया जाता है।

(3) सुची स्तर (Calendar Stage)-प्रत्यक विधयक को समितियो द्वारा सदन को प्रतिवेदन सहित जिस कम से लौटाया जाता है, उसी कम म उनको तीन प्रमुख सुचियो (Calendars) म से एक मे सम्मिलित कर दिया जाता है। तीन प्रमुख सूचिया है (1) सधीय सुधी (Union calendar) इस सूची में सभी सधीय या धन सम्बाधी या अय सावजनिक विधेयक रखे जाते है । (॥) सदन सूची (House calendar) राजस्व, धन या अय वित्त विधेयका के अतिरिक्त शेप सावजनिक विथे यको को इस सूची म रखा जाता है। (m) व्यक्तियत सुबी (Private calendar) इसम सभी व्यक्तिगत विधेयक रखे जाते ह । इसे सम्पूण सदन की व्यक्तिगत विधेयक समिति सुची (Calendar of Committee of the Whole House for Private

Bills) भी कहते है ।

(4) द्वितीय वाचन (Second Reading)—सूची स्तर के पश्चात विधेयक पर मदन मे विचार किया जाता है। इसे विधेयक का द्वितीय वाचन कहते ह । सम्पूण सदन की समिति (Committee of the Whole House) के रूप म सदन का अधि-वेशन प्रारम्म होता है। स्पीकर सदन की पूण समिति की अध्यक्षता नहीं करता है। 100 सदस्या की उपस्थिति गणपूर्ति के लिए आवश्यक होती है। अनीपचारिक रूप में सभी काय चलता है। मौखिक मतदान होता है एवं उसका काई विवरण नहीं रखा जाता है। विधेयक पर विचार विमा समाप्त हा चुकन पर स्थीकर पुन अध्यक्ष का आसन ग्रहण कर लेता है। डितीय वाचन विधेयक की महत्वपूण अयस्या होती है। इस अवस्था म अनक सशोधन प्रस्तावित किय जात ह । विधेयक पर सदन म विचार के समय समिति के प्रमुख सदस्या द्वारा उसका मागदरान किया जाता है। अल्प-

सस्यक सदस्या द्वारा उसना विरोप होता है। विचार विमय्न नी समान्ति पर सदर का अध्यक्ष विधेयन नो ततीय वार पढ़े जाने ना प्रस्तान रक्षता है। यदि यह प्रस्तान स्वीकृत हो जाता है ता विधेयन का तृतीय वानन हाता है अयया द्वितीय वानन म ही विधेयक समाप्त हो जाता है।

(5) तृतीय वाचन (Third Reading)--- यह सदन म विधेयक की अतिम

अवस्या होती है और इसम नाममाप्र का वाचन होता है तया विधेयक का केवल शीपक पढ़वर सुना दिया जाता है। यदि वोई सदस्य सम्पूण विधेयक क पढ़े जाने की मांग परता है तो उसे पढ़ा जाता है। सामायत ऐसी मांग नहीं की जाती है। इसके पहचात विधेयक पर जितम जिणय जानन क लिए अध्यक्ष मतदान कराता है। मतदान की तीन प्रमुख रितियाँ हैं (1) मौजिक मतदान (Viva voce Vole) अपात सदस्या के पक्ष विधेयक को ध्वनि के आधार पर निर्णात किया जाता है, (2) खड़े होकर मतदान (Vote by standing), एव (3) हो या 'न' द्वारा मतदान (Vote in a yes and noes)। 'खड़े हाकर मतदान' तथा 'हा' या 'न' द्वारा मतदान

की रीतियों का प्रयोग सदस्या के मीय करन पर ही किया जाता है। दोनों सदना स विषेयक के पारित हान पर वह राष्ट्रपति क हस्ताक्षये के लिए भेज दिया जाता है एवं तरफरवात वह विषि यनता है। राष्ट्रपति क करना है का पर करना है या उसे सद्योगन सहित पुर्वाविषार हुत वापस भेज सकता है या उसे सद्योगन सहित पुर्वाविषार हुत वापस भेज सकता है या उसे सद्योगन सहित पुर्वाविषार हुत वापस भेज सकता है या असे सद्योग को ह्वीकार कर सकता है। राष्ट्रपति हारा प्रस्तावित सद्योधन को ह्वीकार करें के लिए काग्रेस वाच्य नहीं है। यदि काग्रेस 2/3 बहुम्बर स विश्वयक को पुर्व मूल परित कर देती है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों के विना भी वह अधिनियम का रूप प्रारंत कर देती है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों के विना भी वह अधिनियम को राष्ट्रपति को असनी स्वीकृति अव्यान कर देती नहीं के स्वाविष्ट । यदि इस अवधि के समान होने पर में राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता तो यह माना जाता है कि विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति प्रवान कर दो गयी है और वह अधिनयम वन जाता है। यदि इस अवधि (यह दिन) के अवर काग्रेस का सब समारा हो जाता है और राष्ट्रपति कोई कायवाही नहीं

करता तो विषेयक का स्वत अन्त हो जाता है। सीनेट एव प्रविनिधि सदन मे विधि निर्माण प्रक्रिया सम्बंधी तीन महत्वपूर्ण

ानट एवं प्रतिनिधि सदन में निर्माण प्रक्रिया सम्बंधा तीन महत्वरा अत्तर है। वे निम्नलिखित हैं (1) 1933 ई के पूर्व सीनेट में प्रतिनिधि सदन की अपेक्षा सदन की पूर्ण

सिमिति की व्यवस्था का अधिक प्रचलन था। लेकिन अब सीनेट में सि अयो के सदम में विचार विमान करते समय ही सदन की पूण सिमिति का आयोजन किया जाता है। (2) विमियोग विधेयको (Appropriation Bills) को सीनेट में अनिवायत

(2) विनियाथ विधेयको (Appropriation Bills) को सीनेट मे अनिवायत प्राथमिकता यी जाती है। अय कोई विधेयक विशेष महत्व का नही होता है। अत सूची के कमानुसार या इच्छानुसार विवेयको पर विचार होता रहता है। सीनेट में

व्यवस्थापिका--विवि निर्माण प्रतिया एव सम्बन्धित विपद । ३६७

केवल एक सूची (calendar) होता है। इसे कामभार सूची (calendar of b....: >>) की सना दी जाती है।

(3) सीनट म बाद विवाद को सीमित करने की कोई प्रमावकारी व्यवस्था नहीं है। सीनेट के सदस्य स्वेच्छा पर अपनी सम्मति से ही एमा कर चक्ट हैं।

दलीय समिति प्रणाली (The Caucus System) - चन्न उन्हें उन्हेंदर म विधि निमाण प्रतिया से ही सम्बचित दलीय समिति प्राानी (C. Sussan) है जिसका अमेरिकी राजनीतिक जीवन म विकास हुआ है। कार्रे के क्रिकेट की कि करने एव विरोध करने के लिए आवश्यक नेतृत्व का उनाव है। प्रस्ता हर करने के

लिए एक अन्य व्यवस्था का विकास हुआ है जिस काक्त (C. क्या) का दर्की कुल्लाक (Party Conference) कहते हैं । अनक विषेयक दिर उन्न न के हैं। न विधेयका को पारित करना व्यक्तिगत सदस्या का दाउँस्य हुना है। केकिन कहन्यपुप विधि प्रस्तावों को ऐसे नहीं छोडा जा सकता बार उन्हें इन्बर्ग में कारू प्रस्ता ह सहयोग की अपक्षा की जाती है।

388 | आधुनिय शामात व

सपुक्त राज्य अमेरिका म वित्तीय विधि निर्माण-

अमरिका वित्तीय जिथि नियाण पद्धति त्रिटिश वित्तीय व्यवस्या स प्राप्तत निन्न है। इसका मुस्य कारण यह है कि अमेरिका म ब्यवस्थापिका एवं कायपातिका या गठन शक्ति पृथनकरण पर आधारित है। 1921 ई के पूर्व जमिरिनी वजट-व्यवस्था पर्याप्तन अध्यवस्थित थी। प्रत्येच विभाग द्वारा अपन विभागीय अनुमानो को तयार किया जाता था एव जोपासार निमास थ सचिव (Secretary of the Treasury Department) द्वारा उनको प्रतिनिधि सदन र समदा आगामी वय कं कर-प्रताहा सहित प्रस्ताबित निया जाना था। फाइनर व जनुसार यह अनुमान (Estimates) जव्यवस्थित (uncoordinated) एवं जमशोधित (unrevised) हुना करत थे। । इह प्रतिनिधि सदेन की विभिन्न समितिया के सप्य विचाराथ पितरित कर दिया जाता या । सदत की सिमितियाँ पृथव-यथक रूप म प्रतियदन प्रस्तुत करती थीं । इस प्रकार सम्पूण वजट पर एक साथ विचार नहीं होता था। प्रतिनिधि सदन म वजट पर विचार ही चुकन व पश्चात इसी प्रतिया ना सीनेट स दाहराया जाता था। अत वजटपपक पृथक विचाचीय अनुमानित यांगो का वचल एक समूह मान हुआ करता पा और इतन

नोड त्रमञ्ज्ञता नहीं पायी जाती थीं। 1921 ई वे वजट एवं लेखा अधिनियम (Budget and Accounting Act)

में द्वारा निम्न व्यवस्थाएँ की गयी । ट्रेजरी विमाग के अतगत बजट कार्यानय (Bureau of the Budget) की स्थापना की गयी है 100 इसके अध्यक्ष की निर्देशक (Director) की सभा दी गयी जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है एवं उमी के प्रति उत्तरवायी भी होता है। उसकी सहायताय उपनिवस्त भी नियुक्त किये जाने हैं। निसंक (Director) की स्विति मारतीय वित्त मंत्री एवं बिटिश वित्तमंत्री (Chancellor of the Exchequer) के समान होती है। वह वित्तीय व्यवस्मा स सपना एव मितव्यवहाँ के लिए सदव प्रयत्नशील रहता है। विभिन्न विभाग द्वारा प्रस्तावित व्यय की अनुमानित मीगा की बह उनके सहयान से सतकतापुरक जीच पडताल करता है। जहां वह उचित सममता है इतम कटोती कर सकता है एव विभागों के डारा इस सम्बंध में अधीत करने पर उसका निणय अतिम हुआ करता है। ब्यम की अनुमानित मांचा (Esti

Refer to Finer, H op cut pp 519 523 53 54 Ibid pp 519 520 55

फाइतर द्वारा वजट ब्यूरो को बजट प्रणासी का नारखाना (Workshop of the Budget System) की सना दी है। 1939 ई के पुनगठन अधिनियम के अधीन वजट नामालय का राष्ट्रपति के कार्याक्षय (Executive office) का एक अग बना दिया गया है। स्मरणीय है कि बजट कार्यालय की काई स्वत न अधिकार प्राप्त नहीं है। वह एक जॉन करने वाली सत्ता (investigating and collating authority) है। यह सत्ता भी सामादित

mates) पर विचार के साथ ब्यूरी जाय के स्रोतो-करा-का भी अध्यवन करता है एव कोन से नवीन कर काँग्रेस को प्रस्तावित किय जायें इस पर विचार करता है। आय एव व्यय सम्ब भी सभी ऑकडे तैयार हो जाने पर राष्ट्रपति को काँग्रेस म बजट प्रस्तुत करन सम्बंधी व्यवस्था उपरोक्त अधिनियम के अधीन ही दी गयी है। फाइनर के अन् सार राष्ट्रपति म ही सावजनिक वित्त के सम्बाध म विचार एव तदन्रूप (काँग्रेस से) सिफारिश करने की शक्ति केडित है। 8 अधिनियम द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति के अतिरिक्त अ य कोई अधिकारी या विमागीय कमनारीगण कांग्रेस एव उसकी समितिया स अनुमानित व्यय के लिए धन की माग या प्रायना नहीं कर सकते और उनके द्वारा नवीन कर के प्रस्ताव भी नहीं रखे जा सकत हैं। फाइनर का मत है कि इस व्यवस्था की प्रत्यक्ष मे तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप म उपक्षा की जाती है। 187 स्मरणीय है कि बजट ब्यूरो काँग्रेस के आदेश पर उसे आवश्यक सहायता एव सचना भी प्रदान करता है।"

प्रतिनिधि सदन म बजट प्रस्तावित करने के पश्चात व्यय की अनुमानित मागो को सदन की विनियोग या प्रदाय समिति (Appropriation Committee) के पास भेज दिया जाता है । विनियोग समिति की अनक उप समितियाँ उस पर विचार करती हैं। इन समितिया के ढारा अपने समक्ष अधिकारिया को बुलाया जाता है। उन्हें अपने विभागा की मागा के शौचित्य के सम्बाध म विचार रखन का अधिकार होता है। उप समितिया अधिकारियो द्वारा कमी कभी किसी विशेष मद के व्यय किये जाने के सम्बन्ध म वचन ले लेती हैं। यह व्यवस्थापिका द्वारा प्रशासन पर निश्चण की एक प्रणाली है। सीनेट की विनियोग समिति भी इसी व्यवस्था का अनुगमन करती है। प्रदाय समितिया द्वारा कायपालिका के कुछ प्रस्तावा म कमी तो दूसरा मे वद्धि की जाती है । पोक विधि निर्माण (Pork Legislation) अमेरिकी विधि निर्माण पद्धति की एक विशेषता है। 69 विनियोग समिति सभी अनुमानित मागो को एक विधेयक म सगृहीत करके सदन को लौटाती नही है वरन एक के पश्चात दूसरे करीब 12 अनुमान-व्यय विधेयक सदन को प्रेपित किय जात हैं। प्रतिनिधि सदन म विनियोग विधेयको

⁵⁶ Finer, H op cut, p 520

⁵⁶ Finer, H op cut, p 220
57 Ibid, p 520
58 Ibid, p 520
59 अमेरिको क दक्षिणी राज्या म एक पुरानी प्रचा है कि गुलामा को एक निष्क्रित दिन गोस्त वितरित किया जाता था। यह यास्त पीपा म भरकर खेतो पर जाता था। इसी प्रकार इस उपमा का यदि विधि निर्माण पर लागू कर तो इसका अथ यह हुआ कि अपने निर्वाचन क्षेत्रों को विविध सामाजिक सेवाओं के हिताय पन प्राप्त करते हुतु कावेस का प्रत्येक सदस्य सासन म परस्पर सहयोग करते का प्रयत्न करता है। इस प्रकार निमित्त विधिया पाक विधिया कहताती E 1-Beard C A American Government and Politics, 1955, p 151

390 | जापुनिव सासनन त्र

(Appropriation Bills) र पारित होने व पश्चात उह सीनेट म नेब दिया जाता है। मीनेट की विनियोग मिनित म विचार विमस होता है, महत्वपूण संसाधन कि जात है तथा घन सम्बंधी बटौती या विद्ध न प्रस्ताव पारित हात है। प्रतिनिधि सस्त क निषय में अस नुष्ट वम हारा गीनट म प्रस्त का नय सिर से विचार के तिए उठाया जाता है और उनव द्वारा समिनिया पर दवाव डाला जाता है तथा वाहित संगीपन का प्रयत्न विया जाना है। मोनट हारा विचार कर चुक्ने के पत्थात उसक हारा प्रस्ता वित सद्योधन की स्वीकृति के लिए व्यय विधयक को प्रतिनिधि सदन म पुन नेना जाता है। यदि त्रतिनिधि मन्त्र सीनेट कं संयोधना को स्वीकार नहीं करता तो सन् मदना की एक संयुक्त समिनि (Conference Committee) की नियुक्ति की जाती है। यह सिमित एस समापान की त्रोज करती है जो दाना सदना की माय हा। दोना तन्तो म मतवय हान पर ही विषयक का पारित हो सकता सम्मव है और तमी विवयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति क निरं भवा जाना है। वजट वार्यालय द्वारा प्रस्ता-वित कर प्रस्तावा पर प्रतिनिधि मन्त की उपाय एवं साधन समिति (Wa)s and Means Committee) एवं मीनट की वित्त समिनि (Finance Committee) विचार करती है।

मक्स बेलाफ व अनुमार 'अमरिकी वजट म कांग्रस द्वारा स्वीकृत होने पर ब्रिटिश बजट जसी अनिवाय एकना का जमाव होता है। जिटेन य ज्ञासकीय बहुमत इसका विशेष घ्यान रखता है कि बजट मुल रूप म जैस सदन म प्रस्तुत किया गया हैं उसी रूप म पारित हो। ® अमरिकी राष्ट्रपति यह आगा कमी नहीं कर सकता कि उसक द्वारा प्रस्तुत कर एवं ध्यय क जनुमान स्वीकृत ही ही वार्येग अमिरिकी वजट प्रतिया म विभिन हिता के दबाव पहते हैं एवं नागरीनिय (logrolling) का तीत्र प्रचलन रहता है। वजट की मुख्य रूपनेखा का निर्धारण कृषि श्रम एवं औद्या मिक हिता क मध्य कठोर सीदवाजी के पश्चात निर्धारित होता है। अमेरिकी बजट व्यवस्था म एकरूपता हेतु 1946 ई म विधायी पुनगठन अधिनियम (Legislative Reorganisation Act 1946) पारित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक सन के प्रारम्म म दोना सदनी की विनियोग एव वित्त समितियो के संयुक्त अधिवेदान ही ध्यवस्या की गयी तथा आगाभी वय के प्रस्तावित वजट पर 15 फरवरी के पूब वाप्रस को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देने का प्रस्ताव किया गया है। लेकिन इस अधिनयम को किया वित नहीं किया जा सभा । फतस्वरूप अमरिका में से तुनित बजट अभी क्रवत क ल्या मात्र है। **फाइनर** के अनुसार, 'अमरिको वित्तीय प्रणाली म जनक सुधारा के 60

The Budget as originally offered does not have the compelling unity of the British Budget where the Governmental majority presented — Max Beloff The American Federal Government 1959

परचात आज मो मुख्य कठिनाई बनी हुई है। काग्रेस राष्ट्रपति के प्रस्तावो को अपनो इच्हानुसार परिवत्तित करने का अधिकार रखती है। दोना सदन एव उनकी सिम-तिया ग्रेष्ठ एव स तुलित वजट से कभी भी बाँख-मिचौनी खेल सकती हैं।"⁸¹

वित्त पर काग्रेस का निय नण जनेक दोपो के कारण प्रमावहीन है। सम्बन्धित चप समितिया केवल अपने से सम्बन्धित अनुमाना के अश पर ही विचार करती है। इन उप-समितिया की चैठके गुप्त होती है। मूख्य समिति के सदस्य भी उसमे माग नहीं ल सकते है अत सावजनिक जालोचना के लिए कोई अवसर नहीं होता। इसके अतिरिक्त यह उप समितिया बहुत कम समय म विचार विमश पूण कर लेती हैं, पर तु समिति को प्रतिवेदन काफी विलम्ब से देती हैं, फलस्वरूप समिति के पास इन विभिन उप-समितियों के प्रतिवेदनों म तालमेल स्थापित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं रह जाता है। अनेक विमागीय मागा पर पूज विचार किये विना ही उप समितिया उन्ह रह कर देती हैं और अनेक मदो को बिना विचारे ही स्वीनार कर लेती ह । फाइनर का कथन है कि दोना सदनो की एक हो प्रदाय समिति (Appropriation Com mittee) होनी चाहिए तथा बतमान दो समितिया अर्थात दहरी व्यवस्था ना अत होना चाहिए। किसी भी लोकत तीय शासन म सबुक्त राज्य अमरिका जैसी विनाशकारी दोहरी व्यवस्था नहीं पायी जातो है । 52 1921 ई तक संयुक्त राज्य अमेरिका म लेखा-परीक्षण की व्यवस्था भी दोपपुण थी। वजट एव लेखा-कार्यालय अधिनियम, 1921 ई के अत्तगत मूख्य लेखा कार्यालय (General Accounting Office) की स्थापना की गयी है तथा नियानक एव महालेखा-परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 15 वप ने लिए की जाती है। इस लेखा के सम्बन्ध म ब्यापक शक्तिया प्रदान की गयी है। ब्रिटिश एव अमेरिकन विधि निर्माण प्रक्रिया की तलना

दोना देशा की प्रक्रिया मे कुछ आधारभूत समानताएँ है सेकिन विस्तार की बाता म उनम काफी अ'तर है। समानताए निम्नवत हैं

- (1) दानो देशा म विधेयक के तीन वाचन (Three Readings) होत हैं,
- (1) दाना दशा म निषयक के तीन वाचन (Three Readings) होते हैं, (2) दोना देशों म विधि निर्माण म समितियों की व्यवस्था है।
- (3) दोनो देशा म वित्त-विधेयक सवप्रयम निम्न सदना म ही प्रस्तुत निये जाते हैं।

इसके अतिरिक्त कोई समानता नहीं है। समानता की अपक्षा भेद अधिन हैं

⁶¹ Finer, H op at , p 521

^{62 &#}x27;It has been proposed that the two Houses shall form one Appropriations Committee rather than have a dual and duplicated system as now exist. The crushing duality of the United States system exists nowhere else in democratic government '-Finer, H ob at 19 522.

- (1) अमरिना म इमलैण्ड भी तरह सावजनिक एवं व्यक्तिगत अपवा पासनीय एवं व्यक्तिगत सदस्य विधेयका जस कोई भेद नहीं होत हैं। यह सम्मव है कि नुष्ठ विधेयक ऐसे हो जि हैं राष्ट्रपति या निसी प्रधासकीय विमाग का समयन प्राप्त हो, लेकिन इसका यह अप नहीं है ि ऐसे विधेयक अमरिनी कोग्रेस म पारित हो ही लायें। अभ्य असरिन कर्मार पर राष्ट्रपति हारा इन्द्रित विधेयका केगियक निर्मान करित हो ही सार्वे अभ्य असरिन पर राष्ट्रपति हारा इन्द्रित विधेयका केगियक स्वतावित किय नाते हैं। सदन म उनके सफल परायण (passage) एवं पारित होने के लिए सम्बिण्य विमाग का मान्यो उत्तरवायी होता है। इनलण्ड म विभी सासनीय विधेयक की अस्ती कृति ना अप मित्रमण्डल का पतन है। मित्रमण्डल का सासन हारा प्रस्तावित विध यक्तो के पारित होने के सम्बय्य म सदन म उपलब्ध व्यापक दलीय समयन क कारण पूण निवित्त तता रहती है। इसलैण्ड को तरह अमरिका म कायपातिका के सदस्य—राष्ट्रपति एवं उत्तक मित्रमण्डल के सदस्य —विधि निमाण काय म प्रत्यम रूप स सम्बयित नहीं होते फलत वे कोई योग नहीं देत हैं।
- (2) अमिरिकी काप्रस ने सभी विधेयक व्यक्तियत रूप म सदस्या द्वारा प्रस्ता वित किये जाते हैं। उनके परायण हेतु आवश्यक समयन प्राप्त करन क लिए अनेक सदस्य आपस मे गुट यना लेते हैं एव उन विधेयका का विरोध भी करत हैं जिनक वे विरुद्ध होते हैं। इसे लागरोलिंग (Logrolling) कहते हैं। इस प्रधा का विकास विदिश ससद म सम्मव ही नहीं है।
- (3) दोनो देशा म समितिया विधि निमाण म महत्वपूण भूमिका निप्तार्धी है विकन समुक्त राज्य अमेरिका म समितिया अधिक महत्वपूण एव शिक्तशानी है। घर मिटित म द्वितीय बाचन के उपरा त विधेयक समितियो म भेजा जाता है। इस समय तर उसने आवार मूत सिद्धाता पर सदन मे निषय हो चुकता है। अमेरिका म प्रयम बावन के उपरा त और द्वितीय वाचन के पूज ही विधेयक समितियो म भेज दिया जाता है। अमेरिकी समितियो का ग्रेट क्रिटेन की माति विधेयक को प्रतिवदन सहित अतिवाद स्वत की लोटाना आवश्यक नहीं है। इस कारण अमेक विधेयका की समिति अवस्था म ही हत्या हो जाती है।
- (4) ब्रिटिश संसद द्वारा पारित विधेयको को सम्राट द्वारा स्वीकृत कियाजाना जावस्यक है लेकिन यह व्योपचारिकता मान है। सम्राट संसद द्वारा पारित किसी मी विधेयक को स्वीकृति प्रदान करने से इकार नहीं कर सकता। पर तु अमेरिकी राष्ट्र पित का प्राप्त निषेधाधिकार (Veto) वास्तविक है एवं वह उसका प्रयोग मी करता है।

ग्रेट ब्रिटेन एव समुक्त राज्य अमेरिका की वित्तीय व्यवस्था म निम्न अतरहैं —

(अ) अभेरिका में व्यय के अनुमाना (Estimates) की वजट निदेशक द्वारा

तयार किया जाता है तथा राष्ट्रपति द्वारा वजट काँग्रेस को भेजा जाता है। इगलण्ड म वजट वित्त म नी के द्वारा तैयार किया जाता है और उसी के द्वारा ससद (कामन्स-समा) मे प्रस्तुत किया जाता है।

(आ) अमरिका मे बजट प्रस्तुत किये जाने के बाद प्रतिनिधि सदन की विनि-योग एव साधन समितिया को विचार हेतु शेजा जाता है। इगलण्ड म काम स समा द्वारा 'पूण सदन की समिति' के रूप म पूर्ति एव उपाय तथा साधन समिति के रूप म बजट पर विचार किया जाता है।

(३) इगलै॰ड में काम स समा के सदस्या का वजट के अनुमाना में वेवल कमी या कटौती करने का अधिकार होता है। अमेरिका म काँग्रेस के सदस्यों को वजट म कमी, बढि एव अन्य प्रकार के संशोधन करने के भी अधिकार होते ह।

(ई) ब्रिटिश लॉडसमा को विसीय क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं है, अधिक से अधिक वह विधेयक का पारित करने म एक माह का विजम्ब कर सकती है। इसके विपरीत, अमेरिको सीनेट को विज विधेयका में प्रतिनिधि सदन के समान ही अधिकार प्राप्त हैं। वह उसमें आमूलवूलपरिवर्तन कर सकती है। यहा तक कि प्रतिनिधि सदन द्वारा पारित वित्त-विधेयक को वह अस्वीकार मी कर सकती है। भारत की विधि-निर्माण प्रक्रिया

मारत की विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटिश प्रणाली पर आवारित है। सिविधान म विस्तारपूबक विधि निर्माण प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। गर विसीम विधेयक मारतीय ससद के दोना म से किसी भी सदन म सवप्रथम प्रस्तुत किये जा सकत है। ⁶² विधेयक तभी पारित माना जाता है जब वह दाना सदनों द्वारा स्तोधन या विना सशोधन के पारित किया गया हो। दोना सदन के स्विधित (prorogation) होने पर विचारपीन विधेयक रहे नहीं माना जाता है ⁶⁴ और राज्यसमा म विचारा पीन विधेयक जो लाल्समा द्वारा पारित नहीं किया गया है, लोकसमा के विघटित होन पर समाप्त नहीं होता है। ⁶⁸ लिकन विधेयक के लोकसमा म विचारपीन होने या लोकसमा द्वारा पारित होना पर राज्यसमा म विचारपीन होने पर वह लोकसमा के विघटित हो जान र समाप्त नहीं होता है। ⁶⁸ वित्त दि पट्पति ससद के दोना सदना की विघटित हो जान र समाप्त हो जाता है। ⁶⁸ यदि राष्ट्रपति ससद के दोना सदना की समुक्त वटक युलान की पापणा कर देता है एवं उसके परचान सोकसमा का विघटन हो जाता है वि एसी अवस्था में विचारपीन विवेयक समाप्त नहीं होता है।

संसद द्वारा विधि निर्माण सम्ब धी नियम बनाय गय है। इस सम्बाध म दोना सदना म ममान पद्धति का अनुगमन किया जाता है। दोनो सदनो म विवेयक क तीन

⁶³ Article 107

⁶⁴ Article 107 (3)

⁶⁵ Article 107 (4)

⁶⁶ Article 107 (5)

विषेया का निम्न अवस्थाओं म स गुजरना पटता है—प्रथम एवं द्विगैय बाचन (First and Second Readings), समिति एवं प्रतिवदन स्तर (Committee

and Report Stage), एव ततीय वाचन (Third Reading) (

(1) प्रथम वाचन—सन प्रारम्भ होने पर उस सन के सासकीय विधेवनों की एक सूची प्रकाशित कर दी जाती है। यह आयरपक नहीं कि वह सूची पूच ही हो। प्रथम वाचन के जातात विधेयक का प्रस्तुतीकरण एवं सासकीय गच्छ (Government Gazette) म उसका प्रनाधित हाना आयरपक है। सदन म विधयक के प्रस्तुत किय जान के परचात प्रायना क्यिय जाने पर स्पीकर या सदन ना अयर विधेयक को गज्ट म प्रमाधित करने का आदेता दता है। ऐसी अवस्थान सदन म विध्यक को गज्ट म प्रमाधित करने का आदेता दता है। ऐसी अवस्थान सदन म विध्यक प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करने हतु प्राथना की आवश्यकता नहीं होती। यदि विधेयक प्रकाशन के परचात सदन के प्रस्तुत किया जाता है तो उचक पुत्र प्रकाशन के प्रस्तुत का व्यवस्थनता नहीं होती।

वित्यक को प्रस्तुत वरन का इच्छुक सदस्य या मानी विधेयक को सहत में प्रस्तुत करन की अनुसति मीगता हूं एवं उसका सीपक पढता हूं। मानी कं बिटिस्क अप सभी सदस्य विधेयक की पहन करा की अपनी इच्छा की पूव-सूत्रता देत हैं तथा विधेयक की एक प्रति एवं उसके उद्देश्य एवं कारणों का उत्तेख भी विधेयक साथ सस्य कर देत है। भारत में विधेयक प्रस्तुत करने के समय उस पूण होना वाहिए. इसलैंग्ड की मीति Dummys Bills प्रस्तुत नहीं किय जा सकते। इसके अविस्क कित विधेयकों की राष्ट्रपति की अनुमति द्वारा ही प्रस्तावित किया जा सकता है, उनके सम्या न सन्तात है। उनके सम्या न सन्तात मी होनी चाहिए।

विषयम को प्रस्तावित करते समय कोई बाद विवाद नहीं होता । सामायत विषयम के प्रस्तावित करते के तुरत पश्चात ही स्पीकर सदन के समक्ष उसे स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करता है और सदन इसकी मीधिक रूप से अनुमति प्रदान कर देता है। इस समय मंत्री या विषयक को प्रस्तावित करने वाला अंग्र कोई सदस्य भाषण हीं देता।

लेकिन वभी कभी विधेयक के प्रस्तुतोकरण का भी विरोध किया जा सकता हैं ¹ 1954 ई म निवारक निरोध (संबोधन) अधिनियम (Preventive Detention

- (2) डिलीप बासन—निरिचत तिथि का सदन में विधेयक पर डितीय याचन प्रारम्म हाता है। प्रस्तावक या नीन विकल्या म संविधी एक को स्वीकार करने का अधिकार है (1) विधेयक पर तुरत या प्रविध्य म किसी तिथि पर विचार रिया पाम (2) विधेयक किसी प्रवर सिमित को नेज दिया जाय या वियेयक के अधिकार अनीचित्य के सम्बन्ध म जनमत जानने के लिए उस जनता हा। (3) विवादहीन विधेयका पाम । सामा यत विधेयक का प्रवर सिमित में नेज विया जाता हा। (3) विवादहीन विधेयका पर तुरत्त विचार तहाता हं। पर तु एस वियेयन बहुत कम हात है जल अधिकार विधेयका पर तुरत्त विचार नहीं हाता है। विवादस्त विधेयका रा सामा यत जनता के मध्य जनमत जानने के लिए विविधित कर दिया जाता है। डितीय बाचन की अवस्था म विभियक के आधार नूत सिद्धान्ता पर विचार विभाव होता हं। उस पर धारावार विचार नहीं होता और न इस अवसर पर सधोधन ही प्रस्तुत किय जात हैं। विधेयक के सम्बन्ध एस विचार विधार पर एस विचार के सम्बन्ध एस विचार विभाव होता है। वस्तुत किय जात है। सम्मूण विधेयक पर विचार विमाद होता है ता कि उसके आधार मूत सिद्धाता पर समी सहनत हो सकें।
 - (3) सिमिति स्तर— इनक परचात विधेयक विसा प्रवर सिमिति को भेज दिया जाता हु। मिमिति-स्वर विधि निर्माण प्रतिया की महत्वपूण अवस्था होती है। विधेयक का प्रस्तावक (माजी या सामा य सदस्य) एव विधि माजी प्रवर सिमिति के सदस्य होत है। विधि माजी प्रवर सिमिति के सदस्य होता है। सिमिति क्षारा सत्ताध्य प्रस्तावित किय जा सकते हैं। सिमित के प्रत्येक सदस्य को पुनक प्रतिचदन दने का अधिकार हाता है। सिमित के प्रत्येक सदस्य को पुनक प्रतिचदन दने का अधिकार हाता है। सिमित के प्रत्येक सदस्य को पुनक प्रतिचदन दने का अधिकार हाता है। प्रसित्त की समूण कायवाही प्रकाशित की जाती है एव उसे सदन के समक्ष विचाराय प्रस्तुत किया जाता ह।
 - (4) प्रतिवेदन स्तर —सदन य प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जान क पहचाल मानी या प्रस्तावक सदन हा प्रतिवेदन पर विचार करने की मान कर मदता है। इसके अति-रिक्त विनेयक की कुछ जादता या बिना जादता महित समिति में पुन दिवाराथ भेजन या जनमत चानन के लिए अनदा के भव्य विधेयक को प्रचारित करने की मान मन्त्री या प्रस्तावन द्वारा की जा सकती है। यदि सन्त प्रतिवेदन पर विचार करना स्तीकार कर तेता है तो विधेयक पर धारावार विचार होता है, सदस्यो द्वारा ससोधन प्रस्ता

वित किय जा सकते है और अध्यक्ष को उन्हें स्वीकार करने या अस्वीकार करने के अधिकार होता है। प्रत्यक धारा एवं संबोधन पर मतदान होता है। प्रतिबंदन पिवचार हो चुकने के पश्चात सम्पूण विधेयक पर मतदान लिया जाता है और इन्हें साथ ही द्वितीय वाचन पुण हो जाता है।

(5) तुनीय थासन (Third Reading)—इसके परचात एक पूर्व निर्माणि तिथि को विभेयक का तिथिय बाचन प्रारम्भ होता है। प्रस्तावक विषेपक को पारि करन को मान करता है। इस अवस्था में विभेयक के पक्ष या विपक्ष म तक प्रस्तु। किय जात है। अनावश्यक तकों के लिए कोई स्थान नहीं हाता एवं विभिन्न प्रस्तु। प्रस्तावित नहीं विय जा सक्त । केवल मौश्विक प्रस्ताव रखे जा सकत हैं। सदन म ज स्थित सदस्या के बहुमत स मतदान म स्थीकृत होने पर विभेयक पारित हो जाता है।

एक सदन म विषेयक क पारित होने पर उस दूसरे सदन म विचाराम नेज िंग जाता है। वहा भी उम उपरोक्त पाँच अवस्थाओं म स हाकर भुजरना पडता है र्र उसके परचात राष्ट्रपति के समक्ष स्वीकृति हेतु भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति विधन को स्वीकृत या अव्योकृत कर सक्ता है या भ देश या विना स देश के सधापन प्रता चित करत हुए क्तक को पुनिक्चार के लिए लीटा सक्ता है। चित सदन। द्वाप विधेयक का सशोपन या विना सदोपन क पुन पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपी को स्वीकृति देनी पटता है और विधेयक विधि वन जाता है

गर वित्तीय विधेयका के सम्बाध म सम्माबित दा स्थितिया निम्नलिखित है

(1) यदि विषेयम पर दाना सदना म मतस्य नहीं हाता तो दोना सदना है संयुक्त अधियान म विवाद का निश्चय होता है। संयुक्त अधियान को अप्यशाता तार समा का अप्यश्न अधियान को अप्यश्न तार समा का अप्यश्न अध्यश्न अनुसम्भित म उपाप्पश (Deputy Speaker) करने दे एव लावमान के कायरारी नियम लागू हात हैं। सद्ध अधियान म महाध्य प्रश्न विवाद किया मत्त हैं, पर कु वचन ने ही संगीधन प्रस्तायित शिय जा मत्त हैं, पर कु वचन ने ही संगीधन प्रस्तायित शिय जा मत्त हैं जो वो विवास के निर्माण के स्वाद के स्वाद स्वाद हो। सा विवाद के स्वाद स्वाद के स्वाद हो। सा विवाद के स्वाद के स्व स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के

(2) प्या विभेषताः Bills) वर स्थित तत्त्व तथा प्यक्तिः व 1953 है । इर पुत्र ग्रस्ट को व । साथ

⁶⁷ Article III

⁶³ Article 103

के द्वारा विषेयका एव प्रस्तावों को विचाराथ प्रस्तुत किया जाता है। एक शुक्रवार को विषेयको पर तो दूसरे शुन्वार को प्रस्तावों पर विचार विमग्न होता है। व्यक्तिगत-सदस्य विभेयको एव शासनीय विषेयका को पारित करने की रिति प्राय समान है, केवल योडा अंतर होता है। व्यक्तिगत-सदस्य विषेयक को प्रस्तुत करने की स्वान का साथ उनके उद्देश एक कारणा का विवरण तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति (यदि विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हो) एव विषेयक के वितीय परिणाम का विवरण आदि ससन्त होने चाहिए। यदि विधेयक दोधपूण है या उपरोक्त विवरण में से किसी का अमाव है तो विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती । यदि अध्यक्ष विभेयक को सदन के कायकम में शामिल करना उचित नहीं समक्षता है तो वह उसे उपस्थित करन की अनुमति अस्वीकार कर सकता है। व्यक्तिगत सदस्यों से सम्ब-वित एक 15 सदस्यों सिमिति (Committee on Private Members Bills and Resolutions) होती है जिसके सदस्या को अध्यक्ष द्वारा एक वप के तिए मनोनीत किया जाता है।

विसोध विधि निर्माण

वित्त-विधेयको क लिए एक विशेष एव पृथक प्रतिया का विधान है। सिव-धान के अनुसार वित्त विभेषक राज्यसमा म प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। दूसरे शहरा म, वित्त विभेषक सवप्रयम सोकसमा (The House of the People)—िन्नम सदन—मे ही प्रस्तावित किया जा सकता है। कि इसके अतिरिक्त विना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई वित्त विभेषक और अनुमानित माग प्रस्तावित मही की जा सकती। कि लोकसमा द्वारा वित्त विशेषक के पारित होने के पृश्चत उसे राज्यसमा को जसकी। कि सिफारिशों के लिए फ्रेजा जाता है। विधेषक के प्रारत करने के 14 दिन के मीतर राज्यसमा की विधेषक को अपन सुक्तावा सिह्त वौटा देना चाहिए। यदि विभेषक इस अविष म राज्यसमा हारा नहीं सीटाया जाता तो बहु परित समभा जाता है। पर तु राज्यसमा द्वारा विधेषक को इस निश्चित क्षिप सोकसमा को सीटाने पर निम्म सदन को राज्यसमा की सिफारिश स्वीकरा करने या अस्वीकार करने का अधिकार हैं और एसी ददा म विधेषक दाता सना द्वारा पारित माना जाता है।

सविधान के अनुसार निम्नलिखित मामलो से सम्बद्धित होने पर विवेयक का वित्त विधेयक माना जायेगा ⁷¹

 कर लगाने, समाप्त करने, कम करने या परिवतन अथवा व्यवस्थित करने से सम्बध्ति विशेषक (2) ऋण को व्यवस्थित करने से सम्बधित विधेयक,

⁶⁹ जनूच्छेद 109

⁷⁰ अनुच्छेद 113 (3) और 117

⁷¹ जनच्छेद 110

(3) सचित निधि या आकस्मिक निधि सं सम्बधित एवं इन निधिया म से धन की देनदारी से सम्बर्धित विधेयक, (4) सचित निथि में से धन के व्यय से सम्बर्धिन, (5) किसी व्यय को सचित निधि पर भार घोषित करने या ऐसे व्यय की धनराशि म वृद्धि से सम्बर्धित, (6) सचित निधि, भारतीय सावजनिक लेखा म आय या उसके सरक्षण एव देनदारी सम्बाधी या सघ एव राज्य के लेखा के परीक्षण सम्बाधी, एव (7) उपरोक्त मामला से सम्बिधित कोई अय विधेयक। विधेयक वित्त विधेयक है गा नही, इस सम्याध म लोकसमा के अध्यक्ष का निर्णय अतिम होता है। जुर्माना, लाइ

से स फीस एव स्थानीय सरकारों के द्वारा लगाये जान वाले करा सम्बंधी विधेयनों की सविधान के अनुसार विक्त विधेयक नहीं माना गया है। 72 भारतीय वित्तीय विधि निर्माण प्रतिया ब्रिटिश वित्त व्यवस्था पर आधार्ति

है । दोना एक सी ही हैं । मारतीय वित्त के मूल सिद्धात (basic principles) सक्षण मे निम्नवत है

(1) व्यवस्थापिका द्वारा शासन के विभागा द्वारा तयार किये गयं अनुमानी का परीक्षण किया जाता है एवं वह उनके लिए धन स्वीकृत करती है।

(2) आवश्यक धन की व्यवस्था कसे की जाय यह ससद का दायित्व है। नवीन करा को लगाने एव पुरानो को कम या समाध्त करने का उसे एकाधिकार प्राप्त है। (3) कायपालिका द्वारा स्वीकृत (sanctioned) धन के व्यय की जान पड

ताल ससद करती है।

(4) ससद विभिन विमागो के सावजनिक लेखा परीक्षण की व्यवस्था करती है। भारतीय वित्त व्यवस्था की मुल विशेषताएँ (main features) निम्न हैं

(1) सम्पूण वित्तीय कायकम मि तमण्डल द्वारा तयार किया जाता है। वही उसक लिए उत्तरदायी होता है। अत वित्त के सम्ब व में सम्पण पहल (Initia tive) कायपालिका के हाथों म होती है।

इगलैण्ड के वित्त मात्री (Chancellor of Exchequer) की भाति ही भारतीय वित्त म ती वजट-विनियोग एव राजस्व विधेयक-के लिए उत्तरदायी होता है।

(2) सावजनिक वित्त पर ससद का पूण निय त्रण होता है। उसकी अनुमति के विना सावजनिक घनराशि का एक अश भी व्यय नहीं किया जा सकता और न

कोई कर ही लगाया जा सकता है।

(3) वार्षिक वजट म शासन की े ि के बिना कोई गम्भीर परिवतन नहीं कियं जा सकते। नायपासिना द्वारा ही प्रस्तुत किये जाते हैं। (4) व्यर्थ -मक्ती है ले 🖟

वद्धि नहीं कर सकः

72 Articles 110 (

- (5) सचित निधि के स्थायों भार ³ (Charges on the Consolidated Fund of India) इसलैण्ड की माति मारतीय समद के निय प्रण से परे हैं पर तु ससद को इनम विशि द्वारा परिवतन करने का अधिकार है।
- (6) मारत भे भी इगलैण्ड की माति ससद की समितिया द्वारा वजट प्रस्तावी की परी तरह से छानवीन की जाती है।

वित्तीय विधि निर्माण की अवस्थाएँ—वाधिक वित्त विधेयक (वजट) ससद के दोनो सदनो कं समक्ष विचाराय प्रति वध प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ' मारत मे कितीय वध 1 अप्रैल को प्रारम्भ होता है। मारत का वजट दो मागा—रेलवे वजट एव सामाय वजट (Railway Budget and General Budget)—मे प्रस्तुत किया जाता है। रेलवे वजट का सम्बन्ध रेल विचाय से होता है एव रल म नी द्वारा सामा- यत प्रति वध फरवरी के मध्य मे रखा जाता है। शेष विमाणो के नाय क्या स्व प्रति वध फरवरी के मध्य मे रखा जाता है। शेष विमाणो के नाय क्या सम्बन्धी विवरण वित्त मनी द्वारा प्रस्तुत कियो जाते हैं। सामाय वजट रेलवे वजट के पश्चात प्रस्तुत किया जाता है। दोनो वजटा के पारित होने की प्रक्रिया समान है। वजट म स्पष्ट कप से सचित निधि पर स्थायो भार का एव अन्य अनुमानित व्यया का पृथक उल्लेख किया जाना चाहिए। यव्यित सचित निधि के स्थायो व्यय सदस के से नीइति के लिए प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं लेकिन ससद के दोना सदनों को जन पर वहस करने का अधिकार प्राप्त होता है। शेष सभी व्यय नदुदान की मागा (demands for grants) के रूप से लोकसमा ने प्रस्तुत की जाती है। वीनसमा को उन्ह स्वीकृत या कस्वीकृत या कम करने का वृष्य अधिकार होता है।

वार्षिक बजट निम्न पाच अवस्थाओं म होकर पारित होता है

- (1) बजट को प्रस्तुत करना (Introduction or Presentation of the Budget)—सामाय बजट नित्त मानी बारा प्रस्तुत किया जाता है एवं अपने वजट भाषण म वित्त मानी शासन की मुख्य वितीय एवं आर्थिक नीतियो पर प्रकाश अलता है। बजट की प्रतिया सदस्या के मध्य वितरित कर दी जाती ह।
 - (2) दोमो सदनों मे समान विचार विमन्न (General Discussion in both

⁷³ सचित निधि पर स्थायी भार निम्न है राष्ट्रपति का बेतन, मत्ते एव उनके कार्यानय सम्बय्धी अय व्यय, राज्यसमा एव लोनसमा के अध्यक्ष एव उपाध्यक्ष ना तेतनादि, मारत शासन ऋण भार, सर्वोच्च यायात्यके यायाधीशा का वेतन, उच्च यायात्य के यायाधीशा का वेतन, उच्च यायात्य एवं एकेरल कोट के यायाधीगी ना पञ्चन, निषण्यक महालेखा परीक्षक ना वेतन, अप नाई देनदारी एव व्यय । —Article 112 (3)

⁷⁴ Article 112

⁷⁵ Article 112 (2)

⁷⁶ Article 113 (1) and (2)

the Houses)—वजट के प्रस्तुत करने के पहचात सम्मूण वजट पर दोनो सदमा म विचार विमय होता है। इस समय कोई कटोती या अप सदोधन का प्रस्ताव उप स्थित नहीं किया जाता है। दोनो सदना में पूथक-पृथक तीन या चार दिन तक ममूष व्यय की राशिया पर संचित निधि के स्थायी व्यया सिद्धत केवत सामाय विचार विमस होता रहता है। विभिन्न शासकोय विमायों को नीतिया एव प्रशासन को आचा चना की जातों है। इस विचार विमयें का स्वष्ण राजनीतिक अधिक होता है। इस समय काई मत नहीं निया जाता है। बिटिंग परम्परा का अनुगमन करते हुए विरोधी दला को विचार विमय-काल में अधिक है अधिक समय दिया जाता है।

(3) लोकसभा द्वारा अनुसानों को स्वीकृति (Voting of Demands by the Lox Sabha)—विमिन विमाना की अनुसानित माँगा पर विचार करन के लिए पूपक पुषक समय निविध्वत किया जाता है। अनुसाना (Estimates) पर विचार विमान किया जाता है। अनुसाना (Estimates) पर विचार विमान किया पर विचार कर निवार कर निवार कर निवार किया कि वापिक काय-विवरण को सदस्या के समय विचार कर दिया जाता है। विनिन विमाणे की माँगी पर विचार के समय उनकी तीव आतोषना की जाती है। आलोचना की तीवता तो प्रस्तावित सशोधना पर विचार कि समय अत्यिक्त के जाती है। निविध्वत अविधा में हो प्रारोक विवार के समय अत्यिक्त के जाती है। निविध्वत अविधा में हो प्रारोक विवार के साना पर विचार विमान पूर्ण के जाता चाहिए। नियारित समय के अतिचारित समुद्र (closure) का प्रयोग विचार साता है एव समस्त मागा को एक साथ चाहे उन पर विचार हुआ हो या नहीं मान की स्वीकृति हेतु मतवान के लिए परस्ता कर दिया बाता है।

स्मरणीय है कि राज्यसमा को अनुदाना की स्वीकृति के मस्वाध में कीर अधिकार प्राप्त नहीं है। यह तो लोकसमा का ही एकमात्र विशयाधिकार है।

(4) विनियोग विषेयक (The Appropriation Bills) — लोकसमा इर्ण स्वीकृत सभी अनुमानित माँगा एव सचित विधि के स्थायी व्ययों को एकतित करूँ एक विषेयक क रूप म जिसे वाधिक विविद्योग विधेयक (Annual Appropriation Bill) महत है, लोकसमा के समक्ष स्वीकृति हेतु रक्षा जाता है। सदन के अध्यक्ष इर्ण विथेयक की विनित्र अवस्थाओं के लिए समय निश्चित कर दिया जाता है। द्वितेव वाचन म केवल सामाय बाद विवाद होता है। क्षेत्रस्त उद्देश मदा पर बाद विवाद होता है। जिन पर पहले वहस नहीं होती है। अनुमानित मागो म केवल कभी की माग की जा सकते है। सभी अवस्थाओं म विधेयक के पुजरों के परचात उस पर सदन म सरदान हाता है एवं स्थीकृत होने पर स्थीकर उस पन विधेयक भीषित करता है। इसके परचा विधेयक राज्य समा में अब दिया जाता है। राज्यसमा द्वारा विनियोग विथयक कैं पारित होन पर वह राष्ट्रपति के पास स्थीकृति हेतु भेज दिया जाता है। राज्यस्त

⁷⁷ Article 114

द्वारा स्वीकृति केवल औपचारिक होती हैं। वह पुनिवचार के लिए किसी धन विधेयक को लौटा नहीं सकता। यदि शासन अतिरिक्त घन की जावस्यकता जनुमब करता है ती पूरक मागा के हेतु एक या अधिक विनियोग विध्यक लोकसमा म विनीय वप के अन्त के प्रव प्रस्तुत कर सकता है एव उहें पारित किया जा सकता है।

(5) वित्त विधेयक (The Finance Bill)—वित्त विधेयक में आगामी वेप के करा या कितीय प्रस्तावा का उपस्थित किया जाता है और यह वजट के साथ ही में भारत वा प्रधान करामका भार जगरनका भारत ए भार पर भण भार कार पर संसद म रहे जाते हैं। वित्त विधेयक के द्वितीय वाचन में जसके सामा में सिद्धा तो पर विचार विमय किया जाता है। प्रवर समिति में ही विभेषक पर घारावार विचार

F

होता है। इसके परचात समिति अपना प्रतिबदन प्रस्तुत करती है। प्रस्तावित एण १ का प्रमाण जागा जागा गाजा गाजा गाजा करमा करमा होती है। सिवधान म त्रक (Supplementary), अतिरिक्त (Additional or excess), विशेष (Excep तरण [บणमृद्धायम् वर्षात्रम् (Foles on Account) माना (Grants) हो स्वीकार करने की प्रणाका) १४ जावन १४ णाठ प्रधानसम्प्रणाका नामा (प्राथमक) नामा के विकास है। सामा यत के द्रीय शासन होरा बजट प्रति वय 28 फरवरी को संस्त में चपस्थित हिया जाता है। अते । अभैन से लकर बजट पारित होने की विषि तक शासकीय ध्यव हेतु ससद द्वारा अग्निम मागे (Votes on Account) पारित कर दी जाती है।

13

विधायी समिति-न्यवस्था [LEGISLATIVE COMMITTEE SYSTEM]

समिति व्यवस्था, ह्वीयरे के अनुसार, व्यवस्थापिका के विधि निर्माण काय का प्रमुख यात्र है। विधि निर्माण काय के मध्य म ध्यवस्थापिका को अनेक अवसर प्राप्त होते हैं जबकि वह कायपालिका पर नियातण लगा सकती है। आधुनिक समाज म राज्य के काय क्षेत्र मे बद्धि हुई है। उसे विभिन्न प्रकार की जनेक विधियों का निर्माण करना पडता है। एक ही सत्र म व्यवस्थापिका द्वारा समस्त आवश्यक विधेयका नी पारित कर सकना समयाभाव क कारण प्राय असम्भव है, चाहे इस काय के तिए ससद का अधिवेदात वपपयात चलता रहे अथवा उसके काय करने के घण्टो मवडि कर दी जाये। विधानमण्डलो मे विधि निर्माण सम्बाधी दायित्व के वढने और उरे पती प्रकार सम्पादित वरने के लिए सम्पुट (closure) का अधिकाधिक प्रयोग होने तना या। सम्पुट व्यवस्थापिकाओं क कायाधिक्य (congestion) की कम करने का एक तरीकी होता था। इगलण्ड म नॉम स समा म सम्मुट के विकल्प के रूप में समिति स्पवस्या हो स्वीकार किया गया है। समिति व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य विधि निर्माण काम को हीई करना है। समितियो म विधेयका के सभी पक्षा का भेली भौति निरीक्षण होता है और उनपर व्यापक विचार विमश होता है। ब्रिटिश कॉम स समा, मारतीय लोक्स^{मा}। सोवियत व्यवस्थापिका के दाना सदना सहश वडे या वहद् आकार के सदना म विवार विम" के लिए जावश्यक उपयुक्त वातावरण का प्राय अमाव रहता है। इसके विष रीत, ममिति म विधेयक की प्रत्यक घारा पर चर्चा होती है और मतदान होता है। ममिति-व्यवस्था के विरास के फलस्वरूप व्यवस्थापिकाओ द्वारा विधेयका को अपनी ही अप सस्याओं म भेजनर समय की बचत की जाती है और उस समय में वह अन्य

[&]quot;The chief instrument in this (law making) work is the committee system —Wheare K C Legislatures, p 91

आवश्यक कार्यों को करती है। समितिया द्वारा अय्य समय म विधेयको पर विवार किया जाता है।

समितियाँ सदन द्वारा ही निर्मित को जाती हैं। ह्वीयरे के अनुसार "सिमित का जय उस निकाय अथवा सस्या सं है जिसे जन्य व्यक्तियो या निकाय। द्वारा कोई काय सींपा जाता है। सिमिति मे यह धारणा बद्धमूल है कि सिमिति या ऐसे निकाय या सस्या उस व्यक्ति या निकाय के प्रति जतत उत्तरदायो या अधीन होत है जिनके द्वारा उनकी स्वारणा की जाती है अथवा जिल्ह उनके द्वारा विकिया तथा द्वार्थित सौपे जात है।" इसीलिए फाइनर सिमितिया को केवल सदीधन वरने वाले सहायक निकाय नानता है। सदन द्वारो केवल प्रमुख सिद्धा निकाय नानता है। सदन द्वारो केवल प्रमुख सिद्धा निकाय जाता है। है इंगलण्ड, समुक्त राज्य अमेरिका, फास एव नारत की मिनियं अवस्थाओं का उल्लेख अग्रिस पृष्टो न प्रस्तुत किया गया है।

ग्रेट व्रिटेन की समिति-व्यवस्था

The Committees are merely accordary amendia.

House itself deedes main principles and major experience, H op at , p 489

^{2 &}quot;The essence of a committee is surely that it is a body to wand some task has been referred or committed by some other period of the notion of a committee certics with it the idea to doly being in some manner or degree responsible or subsequence or answerable in the iteration to the body of person was upon committed all powers or duty to it? Whence Government Committee (An Evay on the Erituh Committee pp 5 6

स्थित की जाती थी। अत निरतर बढते हुए कायमार को कम करने एव अवरोध की नीति से उत्पत्र कठिनाइयो के निवारणाय कोई माग खोजना आवश्यक हो ग्या था। 1888 ई म दो स्थायी समितियो (Standing Committees) की स्थापना की गयी। यही स्थायी समितियो का प्रारम्भ था। 1907 ई म दो क स्थान पर चार स्थायी समितियाँ स्थापित कर दी गयी। इनमे से एक समिति केवल स्काटसण्ड क मामलो से ही सम्बधित थी। इस समय तक द्वितीय वाचन के पश्चात गर वित्तीय विभेयका को समितियों में भेजना सामा य नियम वन गया था। 1919 ई मैं समितियों की सरया बढकर 6 हो गयी थी। समिति के सदस्यों की सहया 60 से 80 को घटाकर 40 से 60 कर दिया गया या। स्मरणीय है कि प्रारम्म म यह परम्पत प्रचलित थी कि समितियों में विभिन्न दला के सदस्य कॉम स समा के दलीय अनुपात में ही होते थे जिससे समितियाभी कॉम स समाकालघु रूप मान होती थी। रिसी विशेष विशेषक पर विचार करत समय समिति को अपनी सदस्य सहया के बरावर अतिरिक्त सदस्या को नियुक्त करने का अधिकार था। 1919 ई म जिस प्रकार सि तियों के सदस्यों की सख्या कम की गयी थी उसी प्रकार विशेष सदस्या की सख्या की मी 10 से 15 तक सीमित कर दिया गया था। समितियो के अधिवशन किसी समय मी हो सकते थे लेकिन सदम कं मतदान-काल मे उनके अधिवेशन स्थागत रहत प सिमितियो की सरया 1926 ई म घटाकर 5 कर दी गयी। उनकी सदस्य सक्या हम से कम 30 और अधिक से अधिक 50 निर्धारित की गयी, लेकिन अतिरिक्त सदस्या ^{दी} सरया 10 से 35 तक ही निध्चित की गयी थी। 1946 ई मे स्थायी समितिमा गी सरया 6 कर दी गयी और सदस्य सरया अधिकतम 20 निविचत की गयी। अभिरिक सदस्यो की सख्या भी 30 तक हो सकती थी।

ग्रेट जिटेन की समिति ध्यवस्था के अतगत सम्पूण सदन की सर्विति (Committees of the Whole House), प्रवर मितियाँ (Select Committee) एव काम स समा की सावजनिक विधेयक सम्बंधी स्थायी समितियाँ (Staddill Committees on Public Bills in Commons) होती हैं। प्रवर समितियों अ तगत सत्रीय (Sessional) एव व्यक्तिगत विपेयक समितियाँ (Committees 02 Private Bills) होती हैं। इसके अतिरिक्त दोना सदना की संयुक्त समितियों के उर्ग हरण भी प्राप्त होत हैं। सयुक्त समितियों भे दोनो सदना की प्रवर समितिया ग्रामित होती हैं। अत ग्रेट ब्रिटेन म समिति व्यवस्था निम्नवत् है

- 1 सम्पूण सदन को समितियाँ (Committees of the Whole House) (1) सामा य विधेयन समिति (Committee on Ordinary Bill)
 - (2) वित्त विधयक समिति (Committee on Money Bill) (।) वित्त विधेयक समिति (Committee on Money Bill)
 - (11) प्रदाय समिति (Committee on Supply)

- विधायी समिति व्यवस्था | 405 (us) जवाय एव साधन मिमिति (Committee of Ways and
- 2 प्रवर समितिया (Select Committees)
 - (1) सत्रोय समितिया (Sessional Committees)
 - (1) सावजनिक लेखा समिति (The Committee of Public
 - (11) अनुमान समिति (The Estimates Committee)
 - (11) राष्ट्रीय उद्योगों को समिति (Committee on National
 - (1v) वचानिक बादेश समिति (Committee on Statutory
 - (v) विशेषाधिकार समिति (Committee of Privileges)
 - (vi) सावजनिक आवेदन समिति (Committee of Public
 - (vii) काम स समा सेवा समिति (The House of Commons (viii) विशयज्ञ मिमितियाँ (Specialist Committees)
 - - (b) तकनीकी एव शिक्षा समिति
 - (c) विज्ञान समिति
- (ix) व य समितिया
 - (a) निर्वाचन समिति (Selection Committee)
 - (b) स्वामी बादेखा सम्बंधी समिति (Standing Orders
- (2) व्यक्तिगत विभेयक समिति (Committee on Private Bills) 3 स्थायो समितिया (Standing Committees)
 - (1) सावजनिक विभेयक मिनित (Committee on Public Bills) (2) डितीय वाचन समिति (Committee on Second Reading)
- 4 लॉडसमा म निम्न सत्रीय समितियाँ है Committees on (1) Standing Orders (2) Personal Bills (3) Procedure (4) Offices, (5) Privileges, (6) Journals (7) The Appeal and Appellate Committees, and (8) Committee of Selection निवचित्र समिति निविशेष व्यक्तिमन विधेयक समितियां (Committees on Unopposed Private Bills) के सदस्या

- (3) स्कॉटिया ग्राण्ड समिति (Scottish Grand Committee)
- (4) स्काटिश स्थायी समिति (Scottish Standing Committee) (5) वैल्स ग्राण्ड समिति (Welsh Grand Committee)
- 4 संयुक्त समितियाँ (Joint Committees)

सम्पूण सदन की समिति (Committee of the Whole House)

ब्रिटिश ससद के दोनो सदन पृथक पृथक रूप से अपने को समिति के रूप ह परिवर्तित कर सकते है। सम्पूण गदन के समस्त सदस्य इसमे ज्ञामिल होते हैं और उसकी कायवाही में माग क्षेते हैं। लेकिए यह समिति सदन से मिन होती है। कॉम स समा की सम्पूण सदन की समिति की अध्यक्षता स्पीकर नहीं करता। उसका स्थान उपाय एव साधन समिति (Committee on Ways and Means) का समा पित ले लेता है। यह स्पीकर के आसन पर न बठकर उसकी मेज के समीप रखी क्लक की कुर्सी पर बैठता है। सम्पूण सदन की समिति के समापति की अनुपहियति म उप समापति समिति के अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। स्पीकर का दण्ड (mac) उसकी मेज पर से उठाकर नीचे रख दिया जाता है। सदा के नियमा मं शिथितता औ जाती है। प्रत्येक सदस्य को भाषण की पूण स्वत नता होती है और वह एक ही प्रश् पर अनेक वार बोल सकता है। समिति के रूप म सदन की सम्पूण प्रक्रिया बर्नी चारिक होती है और प्रस्तावों के समधन की आवश्यकता नहीं होती। सम्पूण सदन म समापति कटटर दलीय व्यक्ति होता है और प्रत्येक नवीन ससद के गठन के पश्चात उसका निवाचा होता है। सदन की समिति मे बाद विवाद की सीमित या समान नहीं किया जा सकता है। जब सम्पूण विधेयक पर विचार-विमश हो चुकता है ही सदन के उठने और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने ना प्रस्ताव किया जाता है। ह प्रस्ताव के स्वीकार होते ही स्पीकर अपना आसन ग्रहण कर लेता है और सम्पूण हार्न की समिति का समापति सदन के समक्ष समिति के प्रतिवेदन को स्वीकृति हेतु उपित्र करता है, दूसरे शब्दों म, सदन अपनी ही सिफारिशों को स्वीकार करता है।

एक समय ऐसा था जब काम स सभा प्रत्येक विवेधक पर सम्पूण हार्ग की सिमिति म विचार करती थी। लेकिन स्थायी समितिया के अधिक तोक्रिय हैं जान के कारण सम्मूण सदन की सिमिति का प्रयोग कम होने लगा है। सम्मूण सदन

की समिति के विकास के अनेक कारण हैं

(1) वाद विवाद एव विचार विमर्श हेतु सदस्या की उपस्थित को सम्मर्थ बनाने के लिए सदन को समिति का स्तर प्रदान विचा गया। समिति म कुछ गिन वर्ते सदस्य ही होन पर सभी सदस्या की उपस्थिति म स दह रहता था अत सम्मूण सदन मंत्रीत का रूप प्रदान होने से अधिकतम सदस्या की उपस्थिति की सम्प्रावना स्वामाविक हो जाती है। यही कारण था कि 17वी यताब्दी म विधेयका को सम्प्रव सदन की समिति म हो अंबा जाता था।

(2) सम्पूज सदन की समिति म सदन के समस्त सदस्या को विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। ब्यवहार में इसका यह अब है कि सदस्या के तम् एव विघायी समिति व्यवस्था | 407 प्रमायकारी मुट को विषेयक पर मली भाति विचार करने का अवसर प्राप्त हो

(3) प्राचीन समय म कॉम स समा के सदस्य वित्तीय विषयों को राजा स गुप्त रखना चाहते थे। वे स्पीकर को राजा का व्यक्ति समभते थे अत विजीय भामलो पर एका त म समितिया म विचार करना श्रेयण्कर एव आवश्यक सममन्त्री ये। अतएव स्पीकर को समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। यद्यपि अब स्पीकर के प्रति सचेह को कोई गुजाइस और आवश्यकता नहीं है फिर भी परस्परा आज भी वही चली आ रही है।

सम्प्रण सदन सिमिति को व्यवस्था की स्थापना एव विकास के फलस्वरूप गोपनीयवा तथा लचीली एव अनोपचारिक काय पद्धति सम्मव ही सकी है।

तम्पूण सदन की समिति म महत्वपूण⁵ एव वित्त विधेयको पर विचार किया जाता है। सम्पूण सदन की समिति जब गर वित्तीय विधयका पर विचार करती है तब जरें सामाय विषयक समिति (Committee on Ordinary Bills) कहते हैं। वव किसी वित्तीय प्रस्ताव या किसे विधेयक पर सम्प्रथ संदन समिति के रूप म विचार करता है तो उसे सम्बुण सदन विच-प्रस्ताव समिति (Committee on the Whole House on a Money Resolution) कहत है। जब समिति अनुमानो की मामा (Appropriations) पर विचार करती है तो उसे प्रवाय या प्रति समिति (Committee in Supply or House in Supply) कहते हैं। जब सदन समिति के रूप म राजस्व विश्वेषक वर्षात कर प्रस्तावा पर विचार करता है तब उसे जपाय एव साधन सिमिति (Committee of Ways and Means) कहते हैं।

महत्वपुण कि तु सामा य विधेयक (Ordinary Bill) पर विचार करने के तिए सम्मुण सदन को समिति म विचार का अस्ताव नियमानुसार विसीय वाचन क तुरत बाद किया जाना चाहिए। यदि ऐसा कोई यस्ताव उपस्थित नहीं किया जाता पुरुष नाम विभाग जाति नाहिए। बाद एका व्यव क्रिक्टला व्यवस्था विद्यास्थ्य विद्यास्थ्य विद्यास्थ्य क्षेत्र विद्यास्थ क्षेत्र विद्यास्थ क्षेत्र विद्यास्थ क्षेत्र विद्यास्थ क्षेत्र विद्यास्थ

सावजीनक विधेयको को सम्पूण सदन की समिति म विचार विमन्न हेर्नु भेजने का प्रस्ताद नहीं किया जाता, क्यांकि सम्मूण सेंदन भी समिति की नहर संस्था के

⁵ महत्वपूर्ण विभोगना से वात्पय ऐसे विषयका से हैं जिनका बीद्य पास्ति विद्या महत्वपूण विषयम से वंतिक्य एस विषयका से हैं जिनका थीड़ा पाएत क्या जो विषय के होता है अपना जो तेवश्यक्ति महत्व के होते हैं। इसके अतिहास जो विषयक अस्पायों आदेश को स्वोक्त करते से सम्बन्धित (Bills Confirm-जा (ब्रथक अस्त्रांचा काइन्स) होते हैं जेन पर में संस्कृष सदन की समिति म

कारण उसम विचार विमक्ष के लिए उपयुक्त बातावरण का अमाव हाता है। रावे मधोर का मत था कि "किमी विषेयक पर, चाहे वह कितना ही महत्वपूण क्या न हो, सम्यूण सदन की समिति मे विचार विमक्ष नही हाना चाहिए। सदन को विवेयक पर प्रत्म वादा हितीय वाचन मे किर प्रतिवेदन-स्तर पर तथा अन्त म तनीय वाचन की अवस्था मे विचार-विमक्ष के उपयुक्त अवसर प्राप्त होते हैं। इतना प्रयाप्त है, और फिर विवेयक की व्यापक छानवीन एव उसमे मशोधन का दायित्व तो उन नदत्वा को सीपा जाना चीति हो।"

स्थायी समितिया (Standing Committees)

अधिकाश सावजनिक विजेयको को, जब तक कि ऐसे किसी विधेयक को स्पूर्ण सदन की समिति से भेजने का प्रस्ताव नहीं किया जाता है, सामा यत द्वितीय वार्च के पश्चात स्वयमन स्थामी समितियों को भेज दिया जाता है। प्रारम्भ म केवत 2 स्पर्ण समितिया थी। 1907 ई म इनकी मस्था 4 व 1919 ई म दी भी, पर पुरिवर्ण में प्रारम्भ में प्रवाद के प्रस्ता प्राप्त में प्रवाद के पर प्राप्त में प्रवाद के स्वयं के स्वयं के स्वयं का स्वयं का स्वयं के स्वयं के स्वयं का स्वयं के स्वयं का स्वयं

काम स समा की 5 स्वायी समितिया ह---(1) सावजनिक विधेयक स्वायी समिति (2) द्वितीय वाचन समिति, (3) स्काटिश ग्राय्ड समिति, (4) स्कॉटिंग स्वायी

समिति, एव (5) वत्स ग्राण्ड समिति।

साम्रजनिक विधेपक स्थामी समितिया किसी विशेप प्रकार क विधेयक वर्ष विचार करने क लिए निमित नहीं की जाती और न सम्ब धत विषय के आधार रा उनके कोई विशिष्ट नाम ही होत है। उन्ह नवल एक अक्षर A, B, C मा D से सम्बर्धि किया जाता है। इन समितियो का एक अध्यक्ष एक 20 से 50 तक तस्त्य होते हैं में निवांचन समिति द्वारा प्रत्यक विधेयक पर विचार हुतु पुषक-पुषक मनोनीन दिने को है। एक मन में निमिन हो सक्ते वाली इस अवार की स्वायी समितिया की तर्ब पर कांद्र प्रतिव ब नहीं है। द्वितीय वाचन समिति म निवांचन समिति द्वारा मनोनी 20 से 80 तक सदस्य होत है। इसारिका प्रत्यक समिति म स्कारिक निवांचन समि

⁶ No Bill however important, ought to be discussed in a Committee of the Whole House The whole House has its appropriate opportunities of discussion first on the second reading and then on the Bill as amended at the Report Stage and then on the third reading. These ought to be sufficient and the work of detailed consideration and amendment ought to be entrusted to those members who have special qualifications for dealing with the subject of the Bill "---Ramsay Muir How Britain is Georgial, pp. 158 159

⁷ The British Parliament B I S CRP P 5448 (68) 1968, p 27

अ य सदस्य भी हो सनते है। इस समिति ना काय स्काटलण्ड से सम्बिध्य विषेयका, अनुमानित ब्ययो (Estimates) एव स्कॉटलण्ड सम्बिधी मामला पर विचार करता होता है। स्काधिश स्थायो समिति म स्काटिश विषेयको पर विचार विमश होता है। इसमें स्कॉटिश निर्वाचन क्षेत्रो का प्रतिनिधित्व करने वाले 30 सदस्य होते है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक विषेयक पर विचार हेतु 20 अ य सदस्य मानोति किये जाते है। वेस्त प्रायक समिति से वेस्त निर्वाचन क्षेत्रो का प्रतिनिधित्व करने वाले 36 सदस्य एवं 5 अप मानोति सदस्य होते है। यह विमिति निश्चित तिथिया पर वेस्स मनम पशायर (Monmonthshire) सम्ब ही मामलो पर भी विचार करती है।

स्थायो समितियों में सदस्यों का सामायत बही अनुपात होता है जो सम्पूण सदन में होता है। गणपूर्ति के लिए 17 सदस्या अथवा कुल सदस्य सरया के एक-विहाई सदस्यों में से जो भी सक्या कम हो के बरावर सदस्यों की उपस्थित आवश्यक है। समापित इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अध्यक्षों की सुची (Panel of Charman) में से इन समितियों के अध्यक्ष को स्थोकर नियुक्त करता है। अध्यक्षों की सुची को निर्वाचन समिति द्वारा तैयार किया जाता है।

प्रवर समितिया (Select Committees)

किमी विशेष मामले पर सूचना प्राप्त करने एव उसके आधार पर सदन के समक्ष प्रतिवेदन रखने के लिए सामा यत प्रवर समितियों को गठित किया जाता है। ब्रिटिश ससद के दोनों ही सदना द्वारा अवसर आने पर प्रवर समितिया नियुक्त की जाती है। सम्बिध्य विवेधक पर विचार विमश्न पूण हा जाने पर इन्हें समारत कर दिया जाता है। सन के आरम्म म भी प्रवर समितिया गठित की जाती हैं ताकि उस सम प्रवर्ण होने वाले सम्मावित मामलों के प्रत्यक पहलू पर विचार विया जा सके। इस प्रकार की समितिया ने समीय समितिया (Sessional Committees) कहते हैं। यह पत्र कम के लिए ही गठित की जाती है और सन के उपार वे समाप्त मी हो जाती हैं। अत प्रवर समितिया अस्थायों प्रकृति की होती है।

प्रवर सिमितिया के सहस्या को दलीय आधार पर नियुक्त किया जाता है। सिमितिया में सदस्या की सर्या धदन म विश्वित्र दला की सदस्य सर्या के अनुपात में निष्वत की जाती है। लाडसमा में प्रवर सिमिति की सदस्य सर्या सीमित नहीं है लिकन कोम से सम्वर्त है। लाडसमा में प्रवर सिमितियों में अधिकतम 15 सरस्य हो सकते है। विद्या यदि चिहे तो सदस्य की सप्ता में बुद्धि कर सकती है। विमित्र दला के सचैतका द्वारा यह निश्चय किया जाता है कि विभिन्न प्रवर सिमितिया में उनके दल के कौन स सदस्य अधिक योगसायुवक सिमिति म अपने दायत्व का निवीह कर सकती है। नासकीय दल का सचैतक सदन के नेता के प्रयोगना से सिमित के सदस्या के बहुमत के बार मिति की सदस्य करता है। इसा प्रकार सिमिति के स्वरस्या के विभन्न विरोधी

⁸ The British Parliament, op cit p 27

दला ने सचेतना द्वारा अपन दलीय नताआ ने परामधा स मनानीत निया जाता है। सामायत समिति क सभी सदस्या के नाम सयुक्त रूप मही सदन के समक्ष प्रस्तुत किय जात हैं और बिना किसी बाद विवाद के सदन द्वारा उन्हंस्वीनार कर विवा जाता है।

काम स समा की प्रवर समितिया को सास्य नेन एव प्रपत्रा (documents) को प्राप्त करने का अधिवार होता है। लॉडसमा की सिमितिया को यह प्रतियों स्त्रत प्राप्त नहीं होती है। सामा यत लॉडसमा की सिमितिया के समस गाएटो दर एवं प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए सिमिति के आदेश पर ही सम्बिध्य व्यक्ति उपस्थित होते है। लेकिन सदन के द्वारा आयश्यकता अनुमव करने पर सिमित को तत्सन्य घी आश्री देने का अधिवार होता है। वसी-कमी साहय के हुतु जनता को मी प्रवर सिमित के उपस्थित होन की सुविधा प्रदान को जाती है। लेकिन सिमिति का विवार विवार प्रपत्त पुप्त हो होता है। कोम स समा या लाइसमा के सदस्या का अपनी अपनी सिनिधी म उपस्थित होने का अधिकार होता है, पर सीज यवश वे सिमितियों म उपस्थित होने हीत हैं।

कॉम स समा द्वारा निम्नलिखित सत्रीय प्रवर समितियाँ नियुक्त की जाती है

(1) सावजनिक लेखा समिति (The Committee of Public Accounts)— इस समिति की सवप्रथम 1861 ई म स्थापना की गयी थी। इस समिति को प्रवृ काय यह देखना है कि सदन द्वारा स्वीकृत धनराधि उन्ही मदा म ब्यय होते हैं जिनके लिए उसे स्वीकृत किया गया है। कम्पट्रोचर एव ऑडीटर जनरल के प्रतिद्वा एव सावजनिक 'व्यय या बिनियोग लेखा' (Appropriation Accounts) का सीवि हारा परीक्षण किया जाता है।

(2) अनुमान समिति¹⁰ (The Estimates Committee)—यह मंगी सवप्रमम 1912 ई म स्वापित की गयी थी। इसका व्यय पर निय त्रण होता है। इसमें 43 सदस्य होते ह। इह उप समितियों में विमाजित कर दिया जाता है। ह उप समितिया द्वारा शासन के व्यय के एक एक अब की जाब पढ़तात की जाती है। इस समिति द्वारा सराहनीय काय किया गया है, फतत इसके प्रमाव में भी बिंड ई है। कुछ मन्त्रालया में यह समिति अधिक लोकप्रिय नहीं है। इस समिति का महुव इस कारण है कि यह जासन को सदेव सचेत एव सजग रखती है। अनुमान समिति

हारा अपने प्रतिवेदन में विभिन्न शासकीय विभागों की भूतो एवं गलितयों की और च्यान आकृषित किया जाता है।

(3) राष्ट्रीय उद्योगो की समिति (Committee on Nationalised Indus tries)—यह नवीनतम समिति है। यह राष्ट्रीयकृत उद्योगो के हिसाव किताव की

⁹ Wheare Government by Committee, Chap VIII, 1955, pp 205 243

जाच करती हे और इसके माध्यम से कॉम स समा इन उद्योगो पर निध त्रण रखती है। एक मन मं प्राय एक ही उद्योग की जाच की जाती है।

- (4) वधानिक आदेश समिति¹¹ (Committee on Statutory Instru ments)-इसकी स्थापना 1944 ई में हुई है। प्रत्येक वैधानिक आदेश जो सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, उसकी जान इस समिति द्वारा की जाती ह। लेकिन समिति केवल उन विश्रीप मामला पर ही अपना प्रतिवेदन देती है जा उसके समक्ष विचार हेत भेजे जाते है।
- (5) विशेषाधिकार समिति (The Committee of Privileges)-सन के प्रारम्म में कॉम'स समा द्वारा इस समिति का गठन किया जाता है। इसमें सदन के नेता सहित वरिष्ठतम 10 सदस्य होते है। सदन का नेता समिति का अध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त सदन म विरोधी दल का नेता एव एटानी जनरल या सोलिसिटर जनरल म से कोई एक विधि अधिकारी मी इसके सदस्य होते है। इस समिति के अधिवेशन तभी आहत किये जाते हैं जब सदन के समक्ष विश्वपाधिकार सम्बाधी कोई मामला विचार हेत् आता है।
- (6) सावजनिक आवेदन समिति (The Committee of Public Petitions)-इस समिति में सदन को प्रेषित अमस्त आवेदन पत्र भेजे जाते हैं और वहा इन पर विचार-विमश होता है।
- (7) कॉम स सभा सेवा समिति (The House of Commons [Services] Committee) - यह समिति कॉम स समा मे स्थान एव सेवाओ के सम्बंध म स्थीकर को परामश देती है।

इसके अतिरिक्त तीन विशेषत्र समितिया होती है-(1) कृषि वितान समिति, (2) तकनीकी एव शिक्षा समिति, तथा (3) विज्ञान समिति । इन समितिया की सम्बद्धित विमागों के मित्रया का अपने समझ उपस्थित होकर साक्ष्य देने सम्बद्धी जाजा देन का जिथकार होता है। इन समितियों के अधिवेशन जनता के लिए खुले होते हैं।

इसके जितरिक्त दो और समितिया है (1) निर्वाचन समिति (Selection Committee), एव (2) अस्यायी आदशो सम्ब घी समिति (Standing Orders Committee) । निर्वाचन समिति स्थायी समितियां क सदस्या का चनाव करती है । अस्यायी आदेशा सम्ब वी समिति ना सम्ब घ व्यक्तिगत विधेयना स होता है।

व्यक्तिगत विधेयक सम्बाधी समितिया!2 (Committees on Private Bills)---इन समितिया का उद्देश्य ससद म प्रस्तावितः व्यक्तिगत विधेयका म सम्यःध म निषय करना होता है। इस प्रकार की समितिया की रचना, काय एव पद्धति

¹¹ Wheare of at pp 205-43 12 The British Parliament H I S of at, pp 26 27

सम्बिधित विधेयक के स्वरूप पर निभर करती है अयात प्रस्तावित विता ।
विरोध (Opposed Bill) निया गया है या विरोध नहीं (Unopposed Bill) निया गया है । 'Opposed Bill' वह विधेयक होता है जिसके विश्व सदन म नां ।
दन-पर प्रेमित निया गया हो । यदि विधेयक होता है जिसके विश्व सदन म नां ।
पर तु कांम स समा में साधन सिमित के अध्यक्ष या लोंडसमा म मिनियों के हो अध्यक्ष (Lord Chairman of the Committees) द्वारा यह नहीं बढ़ी कि इसे Opposed Bill माना जाय तो वह विधेयक Opposed Bill गाना जात ।
Opposed Bill से सम्बिध्य सिमित म सदम के 4 सदस्य होते हैं जो ।
सिमित द्वारा चुन जाते हैं । इन सदस्या का विधेयक में कोई व्यक्तिगत या हित नहीं होना चाहिए । Opposed Bill से सम्बिध्य से कोई व्यक्तिगत या हित नहीं होना चाहिए । Opposed Bill से सम्बिध समिति म उपाय एवं सिमिति के अध्यक्ष एवं उपायथक द्वारा मनोनीत 3 अप सदस्य और मी होते हैं।
प्रध्यक्ष इन तीनो सदस्यों को सत्र के प्रारम्भ में निर्वाचन सिमित द्वारा तयार हुं ।
स च चुनता हैं । चांडसमा के व्यक्तिगत विधेयक समितियों म पांच सदस्य हुं है ।

व्यक्तिगत विषेषक समिति के सबस्या का पूण निष्यक्षाता से काम करना अर्व दयक होता है। समिति के समक्ष विधेयक के पक्ष विषयक भ तक प्रस्तुत करने के लिए सम्बर्धित पक्षा द्वारा सुविज्ञ विधिवेत्ताओं का निमुक्त किया जाता है। इन हों

तिया के प्रतिवेदनों को सदन सदैव स्वीकार करता है।

प्रवर समितिया अपनी निष्णक्षता एव सीहाद्रपूण व्यवहार के लिए दिव्या होती हैं। इन समितिया अपनी निष्णक्षता एव सीहाद्रपूण व्यवहार के लिए दिव्या होती हैं। इन समितिया म दक्षीय आधार पर मतदान अपवाद होत हैं। इनम वर्ष गम बहुत मी नहीं होती। इन प्रवर समितियो द्वारा आवश्यक साध्य तेने ए^व सासकीय विभागों का निरोक्षण करन के लिए दूरस्थ स्थानों की यात्रा भी हैं। जाती हैं।

सयुक्त समितियां (Joint Committees)

प्रत्येक समुक्त समिति में दोनो सदना के बराबर बराबर सदस्य होते हैं। समुक्त समिति के सदस्या की नियुक्ति किसी विदाय विषय या विषयेक या ए हैं। प्रकार के सभी विषयेकों पर विचार करन के लिए वी जाती है। समुक्त सिर्मित का निर्माण किसी भी सदन के निवंदन पर किसी विविध्द विषये या विभव हर्ष विचार करने के समिति में भेजने का प्रत्ये विचार हुत किया जा सनता है परदु विपयेग को समुक्त समिति में भेजने का प्रत्ये उसी सदन द्वारा प्रस्तुत निया जाना चाहिए जिसम कि वह सवप्रथम प्रस्तुत किया यादा है। समुक्त के सदस्या को दाना सदना द्वारा पृथम पृथक रूप स निर्वाविद किया जाता है। समिति को दोना सदना द्वारा प्रथम प्रयुक्त रूप स निर्वाविद किया जाता है। समिति को दोना सदना द्वारा प्रथम प्रयुक्त रूप हो ही हैं।

¹³ The British Parliament op est p 28

नोता सदनों की सहमित से ही सिमिति के अधिवेशन का समय एवं स्थान निहिचत -किया जाता है। सिमिति के सदस्या द्वारा अध्यक्ष को चुना जाता है। दोनों म से -किसी एक सदन द्वारा मनानीत सदस्यों में से भी अध्यक्ष को चुना जा सकता है। समी निवय सतदान से होते हैं। जय सदस्यों की भाति अध्यक्ष को भी मत देने का -अधिकार प्राप्त है।

-आवकार प्राप्त है।

सपुक्त समिति का प्रतिवदन दानो सदना के समझ विचाराथ प्रस्तुत किया

, जाता है। समिति का अध्यक्ष जिस सदन का सदस्य होता है, उसम स्वय उसके

, द्वारा एव दूसरे सदन में समिति द्वारा प्रनोनीत किसी अप सदस्य द्वारा प्रतिवदन

, प्रस्तुत किया जाता है।

समीक्षा--महारानी एलिजावेथ प्रथम के समय से ही द्वितीय वाचन के पश्चात विधेयक समिति म भेजे जाते थे और इसे अस्वामाविक काय नहीं माना जाता था । उस समय की समिति की वतमान प्रवर समिति से तुलना की जा सकती है। लेकिन वतमान समिति व्यवस्था का विकास 19वी शताब्दी के अन्तिम चरण म आपरिश राष्ट्रवादियों की अवरोधक नीति के फलस्वरूप ससद के वढत हुए काममार की कम करने का सहज परिणाम है। ब्रिटिश समिति-व्यवस्था अमरिकी एव महाद्वीपीय देशा की समिति व्यवस्था स सवया भिन ह । अमरिकी समितिया अपक्षाकृत स्थामी हैं और उनका सावजनिक नीति के किसी एक पहलू से ही सम्बाध होता है। अमरिकी सिन-तिया शासन की नीति को निर्धारित करती हैं और उसके कार्यों म हस्तक्षेप करती हैं। ततीय फेच गणराज्य के अतागत फच आयोग भी अमेरिकी समितिया की माति ही काय करते थे । लेकिन ब्रिटिश समितियाँ इससे सबधा मिन्न हैं । कॉम स समा की समितिया किसी विषय विशेष की विशेषज्ञ समितिया नहीं होती हैं। वे सदन का लघु रूप मात्र होती हैं। समितिया के अध्यक्ष भी कामन्स सभा के स्पीकर की प्रति-मूर्ति हैं। सिर्मितियाँ स्थायी नहीं होती और न उनका नाई अपना पृथक व्यक्तित्व ही होता है। उनकी सदस्यता म सदव परिवतन हाता रहता है और वे किसी धर्मिर विदीप से ही सम्बन्धित नहीं होते । समितिया वा उद्देश विवेयक को अस्तिम हर्ने देन होता है। स्मरणीय है कि विटंत में प्रथम वाचन र मध्य ही सदन डारा विकेश सामा य सिद्धा ता को निर्धारित कर दिया जाता है। त्रिटिंग समितिया की द्वारा स्वच्यापुवक विधेयक भेजे जात हैं। ग्रामन्स मना की समितिन हरू है। यक मात्र टोली हैं। ने ने निर्माण की समितिन हरू है। यक मात्र होती हैं। वे प्रमुख विधायी यत्र — समद — के सहायक उरकरण को अ कॉम स समा विधि निमाण सम्बधी वपन दायित्व के प्रविप्त सम्बद्धी काम समा विधि निमाण सम्बधी वपन दायित्व के प्रविप्त सम्बद्धी काम सम्बद्धी वपन दायित्व के प्रविप्त सम्बद्धी काम समित्र काम न समा की स्वायी मिमितिया शा एक दोष बहु हा कि है । हाता था । 1047 =

विलम्ब हाता या । 1947 ई स स्थापा मामितिया म गुल दोष बह जा 14 इस विभागीय समाप्त (closure by compartice) विवाद को समाप्त करन क निता मननान की

प्रयोग प्रारम्म हो गया है। सदन द्वारा विभेयक के प्रतिवेदन को उपस्थित करन की तिथि निश्चित कर दी जाती है। समिति को उसी तारीख तक विषेयक को वापस भेजना अनिवार्य होता है। ग्रेट क्रिन्न म समितिया न विधि निर्माण म महत्वपूण भूमिका नियायी है।

सयुक्त राज्य अमेरिका में समिति-व्यवस्था

फाइनर के अनुसार समितियाँ ही प्रतिनिधि सदन की यथाय विधायी निकाय हैं। 15 वुडरो विल्सन समितिया के कटु आलोचक ये। वह उह लघु व्यवस्थापिका (Little Legislatures) कहा करते थे। वृडरो विल्सन द्वारा ही सवप्रथम अमरिकी समिति-व्यवस्था का गम्भीर अध्ययन किया गया था, और यह अध्ययन चिनत कर दने वाला या। मुश्रसिद्ध स्पोकर थॉमस थी 'रीड समितिया को सदन की आखें, कान, हाय व मस्तिष्क वहा करता था। 18 शासन के अध्यक्षात्मक स्वरूप के कारण समिति-व्यवस्था ना समुक्त राज्य अमेरिका म अपना विद्याप महत्व है । इगर्सण्ड म सत्तदीय शासन हाने के कारण अधिकाश विधेयक मिनमण्डल द्वारा प्रस्तावित किये जाते हैं। अमेरिका म शासन व्यवस्था शक्ति-पृथक्करण पर आधारित है एव काग्रेस नेतत्व विहीत है। फलत समितिया का वहाँ विदोप महत्व है। अमेरिकी काँग्रेस म अधिकाश विधयक विभिन मिनिया द्वारा प्रस्तावित किये जाते ह । अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस के नाम भेजे जाने वाले स देशों के आधार पर विभिन्न समितिया द्वारा अपने से सम्बंधित विपेयक वनाकर उन्ह सदन मे प्रस्तावित किया जाता है। काग्रेस मे काय भार अधिक होने के कारण अमितियो द्वारा जिम रूप से विधेयको का निर्माण किया जाता है व अधिकाशत उसी रूप मे विना किसी परिवसन क सदन द्वारा स्वीकार कर लिय जाते हैं। समिति द्वारा विधेयक पर अनुकूल प्रतिवेदन देने पर सदन द्वारा उस विवेचक का पारित होना निश्चित है किन्तु प्रतिकृत प्रतिवेदन की अवस्था मे उस विधेयक की मृत्यु मी निश्चित ही है।

अमरिको प्रतिनिधि सदन ये निम्न छ प्रकार की समितिया होती हूँ ह्यायी समितिया (Standing Committees), प्रवर समितियाँ (Select Committees),

कहते हैं। विचार ने लिए समय निर्धारित कर दिया जाता है। समय के समाज होते ही वाद विचाद समाप्त हो जाता है और उस पर मतदान होता है, मंते हैं विदेशक या उसके किसी अंध पर विचार पूर्ण न हो पाया हो। विक विदेशक की भाराआ पर पृथक-मृथक विचाद होता है अंत इसे विमाणीय समापन की संता मी देते हैं।

¹⁵ The Committees in fact are the real legislative bodies of the House of Representatives —Finer, H op at 1, p 497

¹⁶ Speaker of the House, Thomas B Read described the Committees as the eye the ear the hand and very often the House —Quoted by Finer, H of cf, p 297

सम्पूण सदन की समितिया (Committees of the Whole House), विशेष सिन-तिया एव विशेष जाच समितिया (Special Investigational Committees), सयुक्त समितिया (Joint Committees) एव सम्मेलन समितिया (Conference Commit tees)।

स्यायी समितिया (Standing Committees)

स्थायो समितिया द्वारा विधि निर्माण के काय मे महस्वपूण भूमिका निमायी जाती है। ग्रेट त्रिटेन म केवल 6 स्थायो समितियां है जबिक अमेरिका मे उनकी सरया 34 है। प्रत्यक स्थायो समिति का नाम उन विधेयको पर निमर करता है जो सिनित्या में विचार के अर्जे जाते है। स्मर्पाय है कि 80वी काग्रेस (1946) के प्रतिनिधि सदन म 19 एव सीनेट मे 15 समितिया निश्चित को गयी थी। ¹⁷ इसक पूव 79वी काग्रेस के प्रतिनिधि सदन में 48 एव सीनेट में 33 स्थायो समितिया थी। अनुमानित व्यय (Appropriation), सनिक सेवा वित्त, वैदेशिक मामले, श्रम एव सावजनिक करवाण से सम्बन्धित समितिया सीनट की प्रमुख स्थायो समितिया हैं। इसी प्रकार अनुमानित व्यय (Appropriation), सिक सेवा, उपाय एव सावन, वेदेशिक मामले, शिक्षा एव थम नियम, अत्त राज्योय एव द्वितीय मामले, व्यापार एव वाणिज्य, याय एव सावनिक काय से सम्बन्धित समितिया प्रतिनिधि सदन की प्रमुख स्थायो समिनित्या है।

इन समितिया म सामा यत सदन के दलीय जुगात के आधार पर दोना दलों के सदस्य होते हैं। प्राय प्रत्येक सीनेटर हो समितियों का एव प्रतिनिधि सदन का प्रत्येक सिन्दर होते हैं। इस नियम के कुछ अपवाद मी होते हैं। यह सिमितियों अपने सदन का प्रतिनिधि हव नहीं होती है क्योंकि काग्रेस के सदस्य प्राय उन ममितियों अपने सदन का प्रतिनिधि हज नहीं होती है क्योंकि काग्रेस के सदस्य प्राय उन ममितियों की सदस्यता प्रारत करने के लिए अधिक प्रयत्न करते हैं जिनकी सदस्यता ग्रहण करना उनके निर्वाचन क्षेत्र के हितों की पूर्ति की इंग्टि से अधिक जनुकृत होता है। स्थामी सिमिति में बहुमत दल का वरिष्ठ सदस्य ही अध्यक्ष होता है। यदि वह किसी अप सिमित का सदस्य होता है वे बहुमत दल का ज्य वरिष्ठ सदस्य सिमित का स्वयत्व होता है। वरिष्ठ तो निर्याचन सिमित में प्रीपकालीन सेवा के आधार पर होता है। सिमित के अध्यक्षों का सिमिति के कार्यों पर व्यापक प्रमाव होता है और सिमिति के कार्यों म उनकी जावाज प्रमुख होती है।

स्यामी समितिया का निर्वाचन सदन द्वारा निया जाता है । जिस दल का सदन म बहुमत होता है उस दल का नेता प्रत्येक समिति ने सदस्या की सस्या निहित्तत करता है। प्रत्येक दस सदन म अपनी श्रांति के जनुगात म सदस्या के नामा ना चयन

^{17 89}वी बाँग्रेस (1965) के प्रतिनिधि सदन म 20 और सीनट म 16 स्वायी समितियाँ थी—Ogg and Ray op cit, p 203

कर लेता है और उन सदस्यों को सदल द्वारा निर्वाचित कर लिया जाता है। बत व्यवहार म दोना सदनों की स्थायों समितियों दन के नेताओं द्वारा मनोनीत होती हैं और दोनों सदनों द्वारा उन्हें औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया जाता है। सनी समितियां की सक्या एक समान नहीं होते हैं। सेनीनेट की समितियों की सदस्य-सक्य कम होती हैं, केवल एक अनुमान समिति (Appropriation Committee) म हो 27 सदस्य होते हैं। कोलस्वीय जिला समिति एव नियम तथा प्रशासन समिति म नमा 7 एव 9 सदस्य होते हैं। शेप समितियों में 12 से 17 तक सदस्य होते हैं। प्रतिनिधि सदन की समितियों की सदस्य सख्या सामायत 25 से 34 तक होती हैं जो सीनेट की समितियों की सदस्य सख्या की शुलना में नहीं अधिक है। प्रतिनिधि सदन की अनुमान समिति में 50 सदस्य होते हैं इंजिल नियम समिति में 15 और गर अने समितियों के नाम एक समान ही ह। यहीं नहीं, दोनों सदनों की समितियों के नाम एक समान ही ह। यहीं नहीं, दोनों सदनों की समितियां के काय भी समान हैं। हुंस समितियों है इसका अपवाद हैं।

नियम समिति (Rules Committee of the House) स्यायी समितिया म सबस महत्वपूण समिति है। प्रतिनिधि सदन के स्पीकर एव बहुमत दल के नेता की निर्देशन की जो व्यापक शक्ति प्राप्त है, उसका उपयोग वे नियम समिति के साथ करते ह । सदन के नियमों के निमाण के अधिकार के बारण यह समिति अत्यधिक प्रमाव बाली हो गयी है एव नियमा के निर्माण ने माध्यम स यह विधि निर्माण का नियनित करती है। प्रतिनिधि मदन के काम सम्पादन म इसे निर्णायक अधिकार प्राप्त हो गरे हैं। 1961 ई के पूर्व इसके सदस्यों की सख्या 12 थीं। इस वय स्पीकर रेवन (Rayburn) के नेतृत्व म समिति की सदस्य सम्या की वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया गया था, फलस्वरूप सदस्य सख्या 15 कर दी गयी। विभिन्न समितिया द्वारा विभवनी के पक्ष म जो प्रतिवेदन दिय जाते है उन पर नियम समिति विचार करती है एवं सहन के विचार प्रम को निर्धारित करती है। नियम समिति द्वारा हो यह निरुचय किया जाता है कि प्रत्यक विधेयक पर सदन म क्तिने समय तक विचार किया जाय एवं फौन से सशाधन निये जायें। नियम समिति को यहाँ तक अधिकार है कि वह नये विधेयन के प्रस्तृत करन तक का आदश्च दे सकती है। वह किसी भी विधेयक पर विचार विमर्त को राज सकती है। नियम समिति को यह अधिकार भी प्राप्त है कि वह किसी विधेयक पर सदन म हाने वाली बहुस का स्थागत करक किसी अन्य प्रस्ताव पर विचार करने का बादश दे। सीनट म नियम मिनित के साहस्य काहे अप समिति नहीं है। यहाँ बाद विवार पाण स्वतायाः प्रतिनिधि सदन री नियम की ग्री समिति का विधान प

स्थायी समितियो के अतिरिक्त अन्य समितियाँ निम्नवत है

(1) प्रवर सिमितियाँ (Select Committees)—यह समितियाँ किसी विशेष काय के लिए नियुक्त की जाती हैं एव उस कार्य के समाप्त हो जाने के पश्चात इन सिमितियों का अत्त हो जाता है। अत प्रवर सिमितियाँ अस्यायी होती है। इसके सदस्यों की नियुक्ति सदन के अध्यक्ष द्वारा की जाती है।

(2) सम्रक्त सम्मेलन समिति (Joint Conference Committees)--जन किसी विधेयक के सम्बाध म दोनो सदना म मतभेद उत्पन हो जाता है तो दोनो सदना की ओर से समितिया की नियुक्ति की जाती है और वे दोनो समितिया मिलकर मतभेद को दूर करने का प्रयत्न करती हैं। इस प्रकार की समिति की स्थापना की आवश्यकता सामायत प्रत्येक 10 विधेयको पर पडती है। इस समिति के सदस्य सामायत उन स्यामी समितियों के दोना दला के वरिष्ठ सदस्यमण होत है जिन स्थायी समितियों म विधेयक पर पहले विकार हो चुकता है। सदन को इस समितियों को नियनित करने मे वडी निठनाई होती है। ये समितिया केवल विवादग्रस्त प्रश्नो की सुलकाने तक ही सीमित नहीं रहती। यह बात विशेषकर कर-प्रस्तावों के सम्बाध में अधिक सस्य है। कभी कभी देखा गया है कि दोना सदना द्वारा सरक्षण (protection) की नीति की अस्वीकार कर देने पर अथवा दोना सदनो म कर की दरो के सम्बाध म गम्मीर मत-भेद हो जाने पर इन समितिया ने समभौते के माग का अनुसरण करते हुए कुछ वस्तुओं के सम्बाध में सरक्षण की नीति का समधन किया था एव कुछेक करों की दरी मे बद्धि कर दी थी। इन समितिया के सदस्यों को सन के अन्त काल के समय पर्याप्त स्वत नता प्राप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति मे उनके द्वारा दिया गया प्रतिवेदन अनि-वायत स्वीकार कर लिया जाता है। सयुक्त सम्मेलन समिति अमेरिकी सर्वेशानिक तात्र का एक महत्वपूण अग्र है।

(3) सम्मूण सदन की समिति (Committee of the Whole House)—
इगलण्ड की माति ही अमेरिकी प्रतिनिधि सदन अपने आप को सम्मूण सदन की तमिति
में अनुमान एव राजस्व विधेयको तथा अग्य प्रकार के विधेयका पर विचार हेतु परिवर्गित कर लेता है। 100 सदस्यों की उपस्थित गण्यूर्ति के लिए आवस्यक होती है।
इस समिति को अध्यक्षता प्रतिनिधि सदन का स्पोकर नहीं करता है अपितु अग्य समापति चुना जाता है। इस समिति द्वारा विधेयको का परीक्षण किया जाता है। 1930 है
के पूत्र तक समिति द्वारा प्रस्तुत प्रविवेदन को सुनों के लिए प्रतिनिधि सदन के
सम्मूण सदन ना समिति के रूप म अधियेशन होता था। इस प्रया को सामाग्य वियेयका सम्ब भी प्रविवेदना के सन्य घ में अब त्याग दिया गया है, विन्तु सिपयो पर
विचार करते सम्म आज भी इस परिपादी का प्राचन किया जाता है। सम्मूण सदन
समितियाँ दो प्रकार की हैं—प्रयम, व्यक्तिगत विधेयका के विचाराथ पूर्ण सदन की
समिति, तथा द्वितीय, सावजनिक विधेयका सम्ब भी पुण सदन की समिति।

सण्य की समिति से जोपिकारिक स्थाति से बाद विश्वद्वासी है। से स्वा को सिन से सण्य की अपना अधिक क्षत्रवद्धा प्राप्त होता है। यही क्षत्र मीतिक स्वयत होता है। स्थाप प्रकार प्रतिस्था हो। किये जो सक्षत्र से सूच स्थाप की सीति वै प्रथम सण्या का प्रकार से संस्थान हो बहुत क्षत्र के ज्यसर हो सिन्

बोपम का मिष्यान क अन्तरत विश्वय रूप व बांच की अस्ति प्राप्ति प्राप्ति तारि विधि निमान म उपयोगी एव जाव यह तथा, विचार, मा, पूननाएँ (र परामण बाल्त रिय जा गर । इसर अतिरिक्त, बणासर की भूसा का निरीजन करण इन समितिया ना दूसरा उद्देश्य होता है । इन उत्तरवा की पूर्ति क लिए जांच समिति ना गयुक्त राज्य व अधिनारिया, मी बमण्डल व सदस्या एव जनता क व्यक्ति को संचाई पात करन एव आवश्यक प्रमाण हुनु साह्य दो क तिए अपन समा है स्थित हान का आदेग दा का अधिकार है। समितियां इन व्यक्तियां स आकर्ष मुप्तार्गे पात पर सकती हैं एव प्रपत्रा (documents) की मांग कर सकता है। बीर समितियों जहां आवश्यक सूचना प्राप्त करन य यागदान दती हैं वहां प्रशासन पर की एन अररोध भी है। मुनरा ना मत है नि इन समितिया द्वारा जांच ने बहान अर्ड विरोधिया क विरुद्ध एस अनव अस्य सीज जात है जिनका प्रयोग व अपन विराधिया क पिरुद्ध जागामी निर्माचना म वर सव । " अताएव इन समितिया द्वारा की जाने वाती अचि-कामवाही अधिवास म राजनीतिक हाती है। सीनट के सदस्या का अमरिकी राजनीति म प्राधा य होता है अतएव सानट की जांच-समितिया क तक्य अधिकारि राजनीतिक होत हैं। सानट की जाँच-समितिया ने बड़ा आतक फला रखा है। धान कीय कमचारियो, जिनस प्रधासन म भूल हाना अस्वामाविक नही है, काँग्रेम के विरोधी मदस्या नी पूछताछ से घवडात रहते हैं। जीच-समितियों के अधिवेदान सावजितक

^{19 &#}x27;What they often are seeking is ammunition that can be used in the neat election campaign"—Munro The Government of the United States p 303

ाते हैं, जत इन समितिया के समक्ष साध्य दन म इन्हरूज कर्नच र विद्रोप नव ह कराते हैं एव चिन्तित रहते हैं। बाह चरित्र-हत्त की की बानका हुने रा। जाच-समितिया की काय-मद्धति एकना हो होने न्योंक कार केर प्रकार

त मामला से सम्बाध होता है । सदस्यों के नर्डों ने उन्नर की उन्नर हाईनार्डांत्र का

क प्रमुख कारण है।

समितियों के अधिवेशन पूज या नवजनेक स्माने न नवन है । स्नापा तमितियो द्वारा अय व्यक्तिया का साम्य के बा कर्ज र १ अधिपतने हा दिसम्ब रखा जाता है एवं उनके द्वारा विचा-चिन्हें के उनके काँग्रेग का जॉनक्टर प्रथम क्या जाता है। सामापत महत्त्वपुर विदेशों 🗂 बहुर 😘 उरावर अपूरी

अलग जलग प्रतिवेदन प्रस्तुत काह है जिस्स इसका सामा हराइ स्था हरा है । महत्वपूर्ण विधेयको म सामापन अभिना हुए गुरु न स्वापन स्वेतुर हिन्न जात हैं।

को यदि चाह तो संशोधित कर सकती है, उन्हें अपने प्रतिवेदना सहित वापत क सकती है या स्वीक्रत एव अस्वोक्तत बरने की सिफारिश कर सकती हैं। यह मी सम है कि समिति अपना प्रतिवेदन ही प्रस्तुत न करे। ऐसी स्थिति म विधेष्रक की सीर्मा अवस्था मे ही मन्यु हो जाती है। समितिया के अतिम विचार विमग्न पुष्ट हात है प्रतिवेदनो को विचा किसी संशोधन के ही सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। स्पट है कि विधि-निर्माण में प्रतिनिधि सदन की समितिया महत्वपूर्ण कृतिन

लेकिन सीनेट की समितियों को विधेयक पर इस प्रकार की जीवन एवं मरण की शिल्प प्राप्त ने होते हैं अत वे सवनवाहर्य सर्या म कम होते हैं अत वे सवनवाहर्य सिंध्यम को जाव करते हैं। सीनेट की किसी समिति का एक विधेयक के प्रकार किया प्रत्य के स्वाप्त की जाव करते हैं। सीनेट की किसी समिति का एक विधेयक के प्रकार किया प्रतिवेदन सदन द्वारा उस विधेयक को पारित कर देने की गारण्टी नहीं हाता है। किसी विधेयन पर यदि प्रतिनिधि सदन की कोई समिति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं हाती वा प्रतावक विधेयक को सदन में पुन उपस्थित करने की मान सदन के कुल सदस्य के यहुनत के हस्ताध्य प्राप्त करके कर सकता है। यह प्राय कठिन होता है। सीक

रुद्धार के लिए सीनट के आधे सदस्यों का समयन प्राप्त कर मकना विशय कंडिन की

नहीं है ।

समीक्षा—वीयव⁸¹ के जनुसार "समितिया उच्च विद्यापिकार का उपीर
करती हैं और उनकी कायवाही पुप्त ट्रोती हैं । समितिया पर लावीस (lobbus) के

बडा प्रभाव होता है, फलस्वरूप सम्प्रण समिति-व्यवस्था की विधि निर्माण यन के हो

से तीय काजाजना की गयी है तथा प्रतिनिधि सदन में अन्यसम्प्रणे द्वारा निर्दर्श समितियों के विद्या विद्याप स्तिनिधि सदन में अन्यसम्प्रणे द्वारा निर्दर्श समितियों के विद्याप प्रतिनिधि सदन में अन्यसम्प्रणे द्वारा निर्दर्श समितियों में विद्याप प्रतिनिधि सदस्य के विद्याप विद्याप करते हुए कहा विद्याप के विद्याप को विद्याप निष्य के विद्याप की सक्षा ते विद्याप निष्य के विद्याप की सक्षा ते विद्याप निष्य के विद्याप निष्य के स्वाप के विद्याप निष्य की सक्षा ते विद्याप निष्य की स्वाप ते सक्षा ते जाति है, जब कि इन पर काई भी सदस्य कोई निर्वात निष्य निर्मित व्यवस्था की मुद्य अन्यापनाए निम्मवत है

(1) सिमितियों के फलस्वास्य अमेरिकी यतिनिधि सदन का महाव कम हो गर्यो है। सदन तो दीयद के अनुमार सिमितिया ने निष्णया नो केवल स्वीकृति प्रदार्व नरता है।

²¹ Beard, C A op cut, pp 161 62

- (2) समितिया के द्वारा जो बत्तिम विचार विमक्ष एव निणय किये जाते है वे गूगरूपेण गुप्त होते हैं। सिमितियों में विचार विमक्ष के पश्चात सदन में विधेयक पर होने वाला विचार विमक्ष कर स्वेत विधेयक पर होने वाला विचार विमक्ष अरात्म अरात्म अराम्पद सह- योगपूवक काय मी नहीं करती हैं। उनमें एक दूसरे के प्रति तिकक भी सम्मान की मावना नहीं होती। व्यवहार म प्रतिनिधि सदन म उत्तरदायित्व 19 सिमितियों रूपी मागों में विमाजित हो जाता है। प्रत्येक सिमिति द्वारा विधेयक तथार किये जाते हैं। शैर सम्बित्य मामला एवं नीति की एकता सम्बधी प्रत्ना को व्यान में नहीं रखा जाता है। ऐसी स्थिति में विधि निर्माण में "एरस्पर स्रथ्य (conflicts), विरोध (contra diction) एवं मतभेच (confusion) अनिवाय है।" ह इसके अतिरिक्त विधि निमाण में दलवा दी शी मावनार्य सनिय हो जाती है।
- (3) अमेरिको समितियों का आकार बहुत छोटा होता है अत य सदनों के समस्त वर्गो एव हितों का प्रतिनिधिस्त नहीं करती । फाइनर के अनुसार, "समितिया राप्ट्र के प्रतिनिधिस्त की हृष्टि से बहुत छोटी है। अय देशों की व्यवस्थापिकाओं से सुलता को हृष्टि से औसत रूप मं अमेरिकी समिति में 21 सदस्य होते हैं जबिक फार स म 44 और इनलण्ड म 50 सदस्य होते हैं। 1783
- (4) सिनितिया म अत्यधिक समय, वन एव बुद्धि का अपन्यय होता है। 1946 ई म पुनावन अधिनियम (Reorganisation Act) द्वारा सिनितिया की सप्ता की कम करते का उद्देश विधि निर्माण म समय एव धन के अपन्यय को रोकना माँ था। सिनित्या के अपने मुस्तिज्ञ कार्यां तथ होत हैं। कार्यां तथा के सिन्या एव स्टेशनरी तथा। क्षिमित्या के अपने मुस्तिज्ञ कार्यां तथ होत हैं। अधिकाश सदस्य अपनी पत्तिमी और सम्बिध्या को लिए भन्ने जादि विथे जात है। अधिकाश सदस्य अपनी पत्तिमी और सम्बिध्या को लिए भन्ने जादि विथे जात है। अधिकाश सदस्य अपनी पत्तिमी और सम्बिध्या को लिए एव सहायका के वर पर नियुक्त कर लेते हैं। धन का दुरुपयोग होता है और वह ध्यय के कार्यों पर ध्यय होता है। आलोचना से कान पर जू भी नहीं रेगती। समता के लिए मितब्ययता आवस्यक होती है, लिक्त इस क्षेत्र में मिनवस्यता सम्मव नहीं होती क्योंक सदस्यगद्या के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्रों के मुक्क ध्यक्तिया को और कमी-कमी अपने रिस्तेदारों को नियुक्त करना आवस्यक हो जाता है। "

²² Thus, under these conditions 'conflicts, contradiction and confusion in legislation are inevitable'—Beard, C A op at, p 161

²³ The committees are too small for due national representativeness. The contrast with the legislatures of other countries in this respect 21 compared with 44 in France, and 50 in Britain —Finer, H of cit, p. 498.

^{24 &}quot;Each Standing Committee has a well furnished office Many pre requisites are appreciated by the members, that is, allowance for secretaries, stationery and other purposes Often members employ their wives and relatives as clerks and assistants Undoubtedly, money is wasted on useless activities, but criticism of the system fall on deaf ears"—Reard, C A path p 158

422 | आधुनिक शासनत त्र

(5) समितियाँ अपना काय बहुत धीमी यति स नरती हैं, एनत समय ना अपन्यय होता है। स्वायी एव विशेष समितिया नी नाय-यद्धित, प्रमावशीलता एव मावना म प्याप्त अत्तर होता है। समितिया म विधेयका न सम्बाध म प्रस्तुत किंग जाने वाले साध्य ॥ सम्बाधित चर्चा होती है। समितियाँ नैतिक एव विधिक अधिकार्य को तिनक भी मायता नहीं देती हैं।

दोना मदना की समितियाँ अधिकारिया एव नागरिया के लिए अवग्यतग अधिवेदान करती हैं और इस प्रकार अपन समय का दुरुगयोग करती हैं। यदि धर्मित का कोई सदस्य उत्तेजनायुक्त व्यक्ति होता है (अधिकाशत विदेश समितिया क सदस्य ऐसे ही व्यक्ति होते हैं), तो समिति की स्थिति और भी दयनीय हा जाती है। ऐसी अवस्था म ऐसे अहकारिया (egolisis) के नाम समाचार-पत्रा म मोटी मुखियोग प्रदट

होते है और उन्ह नुठी विचित्त प्राप्त होती है।

(6) सिमितिया के समापति वरिष्ठता नियम (Seniority Rule) के अनुनार नियुक्त होते हैं जिसके फलस्वरूप योग्य व्यक्तिया की अध्यशता करन के अवतर प्राव नहीं होते हैं। फाइनर के अजुसार वरिष्ठता यायता की गारण्टी नहीं है। बिंध तस्वयों का अपने समय और राष्ट्रपति की गीतिया से सहानु मृति का होना अधिक किंव होता है। किंकन इस सम्बन्ध म यह भी विचारणीय है कि समितिया क कथ्या के निर्वाचन के लिए फिर किस सिद्धान को अपनाया जाय । क्लिंग क्षा पढ़ाना है। खें के जाना मी किंव है। यदि उपयोगिता के सिद्धान्त के आधार पर अध्यक्ष की विश्वक्ति का निक्चय किया वाता है और योग्यता के निर्योरण का अधिकार दसीय सिनित के का निर्वाचन किया जाता है और योग्यता के निर्योरण का अधिकार दसीय सिनित के हां स्वाचित की होती की सिन्त की स्वाचित की होती होती की सिन्त की सिन्त की सिन्त की स्वाचित की होती होती होती होती होती है। सिन्त की सिन्त की स्वचस्थापिका का स्वाची बना है। होगा।

विष्ठता नियम का एक अय दोष मी है। इस व्यवस्था के फलस्वरूप प्रमण् और उसके अनुपाधिया म आवश्यक एकता का अभाव होता है। इसके अतिरिक्त इससे सिमितियों एव राष्ट्रपति के विधायी नेतृत्व के सम्ब धो म बाधा पहती है। सिमिति के सदस्यों के बहुमत पर अध्यक्षी का नियायण नहीं होता है। शदस्यण सिमिति के अध्यक्षों को अथदस्य नहीं कर सकते और न वे नये अध्यक्ष को निर्वाधित हीं कर सकते हैं। प्रस्त यह है कि इस सब के वावजूद स्व का नत्युक्त क्या इस नियम के विरुद्ध विद्धोह क्या नहीं करता। फाइनर के अनुसार इसके निम्न कारण हैं (1) नत्युक्त सदस्यों को विधि निर्माण एव सदन को काम पदित का अनुमत होता है। (2) विष्ठि सिक्त सिनेट के सदस्या को अपेक्षाइत दीधकालीन सेवा का अनुमत होता है। (2) विरुद्ध सदस्य दल के पुराने अनुमयों नेता होने के कारण अधिक शक्त जीवन करते में सफल होता है। (3) विरुट सदस्यों को बेवा एव समयन करके उनके निकटतम अनुपारी

²⁵ Finer, H op cst, p 499 26 Finer H op cst, p 499

उचित अवसर पर उनसे वाश्वित लाम एव पुरस्कार की आशा रखते है । (4) यह परम्परा स्वय म पर्योप्त दीघकालीन होने के कारण एक शक्ति वन गयी है।

फाइनर²⁷ का मत है कि 1946 ई म सिमितिया के पुनगठन द्वारा उनकी सस्या अवस्य कम कर दी गयी पर तु सिमितियो को सदस्य सरया वही वनी रही है। विशेषज्ञ कमचारियो की नियुक्तिया योग्यता एव स्थायी आधार पर की जाती हैं। पर तु विरुद्धता नियम म कोई परिवतन नहीं किया गया है। यह खेदजनक है कि जहा तक सिमितिया का प्रश्न है इस विधि का केवन आश्विक पालन हुना है।

उपर्युक्त आ नोचना के होते हुए भी अमेरिकी विधि-ध्यवस्था में सिमितियां का विशेष स्थान है। उनकी महता फाइनर के निम्न कथन से स्पष्ट है ''समी विभेषक सिमितियां में मेंने जाते हैं। सिमितियां का अब स्थायी सिमितियां है क्यांकि सम्पूण सदन की सिमिति को जायद हो कोई गैर वित्तीय विधेषक मेंना जाता हो। यदि मेंना भी जाता है तो उस विधेषक पर स्थायों सिमिति उसके पून ही विचार कर चूनती है। विधेषक के पारित होने म सिमितियां अनिवाय अवस्था है। परम्परा ने उन्हे ययाय एवं व्यवहार में (In substance and form) विधि निर्माण का मुख्य "यायाधीश वना दियां है। ²⁵⁸

ऑग एव रे न जमेरिको समिति व्यवस्था के पक्ष म उसके समयका के निम्न-लिखित तक दिये हैं

- सिमितिया ने राष्ट्र की भली माति सेवा की है और विधायी प्रिक्तिया म ययाथत कोई व्यवधान नहीं पडा है।
- (2) समितिया इसकी प्रतिमृति है कि काबेस म अनुभवी ध्यक्तियो का प्राधाय रहेगा।
- (3) समितियाँ प्राथमिकता की हप्टि से निष्पक्ष एवं वस्तुगत मानदण्ड का निर्घारण करती हैं। इससे व्यक्तिगत कटता एवं पड़य तो को कोई स्थान नहीं रहता।
- (4) समितियों का श्रेष्ठ विकल्प जो अधिकाश सदस्यों को स्वीकाय हो, अभी तक प्रस्तावित नहीं किया गया है। 20

फ्रान्स मे समिति-व्यवस्था

फा स ने ऋति-फाल से ही समितियां फ्रेच ससदी का अभिन्न अग हैं। इनका नाय विधि निमाण के पूच सामाजिक स्थिति की समीक्षा एव असेम्बली से काय का सशाधन करना था। फच समितिया के बतमान स्वरूप की स्थापना 1848 ई तक हो चुकी थी।

²⁷ Finer, H op at, p 499

²⁸ Ibid , p 497

²⁹ Ogg & Ray Essentials of American Government, 1967, p 205

चतुष गणराज्यीय सविधान के अत्तगत विधेयका एव विधि प्रस्तावा क अध्य यन के लिए प्रत्येक सदन को पृथक पृथक समिति व्यवस्था की स्थापना का निर्देश दिया गया था। 1848 ई से ही फांस म यह विवाद का प्रश्न रहा है कि समितिया का विषय या क्षेत्र क्या होना चाहिए ? अमेरिकी कांग्रेस की समितिया वी नांति ही उ हं गठित किया जाय और उस नाय विद्येष के समाप्त हो जाने पर समिति को नी भग कर दिया जाय या स्थायी समितियों का निर्माण किया जाय। स्मरणीय है कि स्थायी ममितिया का विचार प्रारम्भ मे कास मे स्वीकाय नही या। 1898 ई म फेंच संतद में आयोगा (Commissions) की प्रथा का विकास हमा या और 1902 इ में आयोगा को स्थायी बना दिया गया। सदन (Chamber) के नियमा म परिवर्तन करक आयोगों के सम्बाध में आवश्यक व्यवस्था की गयी। 1910 ई में आयोगा की स्यापना की प्रचलित व्यवस्था को ब्यूरा (Bureaux) के द्वारा समाप्त कर दिया गया। लेकिन 1919 ई तक सीनेट म आयोगाकी स्यापनाकी प्रणालीको समाप्त मही किया गया था। फाइनर के अनुसार, "इन दो सुधारों के फलस्वरूप ससदीय आयोगा के जाधुनिक आधार—दलीय स्वरूप एव स्यायित्व—की स्यापना हुई थी।"" लेकिन 1946 ई म फ्रेंच सविधान म आयोगा का उल्लेख किया गया था। प्रच समद के आयागी का कायकाल एक वर्ष होता है। स्मरणीय है कि 1902 ई तह वे विधानमण्डल के सम्पूण कायकाल के लिए निर्वाचित होते थे। लेकिन 1920 ई म जनका कायकाल एक वप कर दिया गया था। 1947 ई के नियमानुसार एक वर की अल्प कायकाल ही कायम रखा गया यद्यपि इसकी तीद बालोचना की गयी वी । फांस में आयोगों की बुल सरया 19 है। इनको असेम्बली के सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। प्रत्यक आयोग मे 44 सदस्य हाते हैं। प्रत्यक फेव सम दीय राजनीतिक समूह द्वारा सदन मे अपनी सदस्य सरया के अनुपात मे आयोग में सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। लेकिन जिस राजनीतिक समृह के 14 से कम सदस्य होते ह उसे आयोग य कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है । स्पट्ट है कि समितियो का गठन समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। यह व्यवस्था द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात अपनायी गयी थी जिससे राजनीतिक दला की और अधिक विधटन न हो । छोटे छोटे समूह आपस म मिलकर प्रतिनिधित्व के लिए वाता कर सकते है। प्रत्येक आयोग मे 4 पदाधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, रेपोर्टियर (Rapporteur) एव मिनगण होते है। अध्यक्ष समिति का प्रमुख होता है। वह सदस्या एव शासन की अय सस्याजा-असेम्बली एव मि तमण्डल-के मध्य सम्बच स्थापित करता है। आयोगो के अध्यक्षों का पद सत्ता एवं प्रमाय का होता है एवं पर्याप्त महत्वपण है।

³⁰ Finer H op cat, p 494

आयोग का अध्यक्ष वासकीय दल का ही होता है। इसके कारण निम्मलिखित है (1) बात्तन पर प्रतिबन्ध रखना एव रखने की इच्छा। (2) मित्रयों के
समान एव प्रतिस्पर्धी पदा की स्थापना। स्मरणीय है कि सभी विधायकों के लिए
मानी पद प्राप्त करना कठिन ही नही असम्यव है। अत आयोगों की अध्यक्षता प्रदान
करके बासकीय दल के महत्वाकाधी सदस्यों को स तुष्ट किया जा सकता है। (3)
सदस्यों के पान एव अनुमव से लामाबित होने की कामता। स्मरणीय है कि आयोग की अध्यक्षता मिद्य में मानी पद के लिए प्रशिक्षण का काय करती है। रेपोटियर
(Rapporteur) का पद मी महत्व का है। उसका काय नीति की हष्टि से आयोगा
के कायों का मागदशन करना है। यह पद भी प्रतिष्ठा एव सत्ता का है।

शासकीय एव गैर शासकीय सभी विधेयका को सम्बन्धित आयोगी की भेज दिया जाता है। चेम्बर (प्रथम सदन) का अध्यक्ष यह निश्चय करता है कि कौन-सा विधेयक किस आयोग को भेजा जाय। यह अनिश्चितता उत्पन होने पर कि अमुक विधेयक को किस आयोग के पास भेजा जाय या कोई विधेयक दो विशेष आयोगा से सम्बर्धित है, सदन मतदान द्वारा अन्तिम निणय करता है। सामा यत विधेयका की आयोगा के पास भेजत समय उनकी वापसी की तारीख तिश्चित कर दी जाती है। सामा यत आयोगा द्वारा तीन भाह के अन्दर विधयक को लौटाना जनिवाय होता है। पदि आयोग निर्धारित जबधि म विधेयक को सदन से बापस लौटाने में असमय होता है तो शासन या सदन के 50 सदस्या को विशेषक की वापसी की माँग करने का अधि कार होता है। विधेयक पर विचार के लिए आधागों के अनक सम्मेलन हात है जिनमे विधेयक पर बाद विवाद होता है। प्रस्तावा एवं संशोधका को आयोग के समक्ष जपस्थित होकर अपने पक्ष को प्रस्तत करने का अधिकार प्राप्त है। आयागा के प्रति-यदना को प्रकाशित किया जाता है तथा सदन म विचार विमरा के पूब वे सदस्या म वितरित कर दिये जाते हैं। फाइनर के अनुसार य प्रतिबेदन ब्रिटिश एव अमेरिकी समितिया द्वारा दिये जाने वाले प्रतिवेदना की अपक्षा कही अधिक सूचनाओं सं युक्त होते हैं। आयोग अपने समस्त निषय एक इकाई के रूप म करता है। आयोग के निणम से असहमत अल्पसन्यक सदस्या का अपना प्रथक प्रतिवेदन दन का अधिकार नहीं हैं।

असम्बनी म विधेयक पर निधारित दिन विचार विमय हाता है। आयोगा के रोगेटिया द्वारा सदन के बाद विवाद म प्रमुख नाग तिया जाता है। नियमानुसार रोगेटियर एव आयोग न अध्यक्ष को याद विवाद की किनी भी अवस्या म हस्स्तेश मा अिपकार होता है। सदन के अल्यसस्य एव उनका प्रतिनिधित परन वार्त सदस्या का परम्परानुसार दिवार-अनिव्यक्ति की विग्न मुविचाएँ प्रदान की जाती है। समस्त जायोगा के अध्यन "अध्यक्षा वा सम्मतन" (Conference of Presi-

dents) वे सदस्य हान हैं। जायोग व अध्यक्षा के अलावा 🚨 उपाध्यक्ष एव सभी

स्वोक्तत दलीय समूहा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी इस सम्मतन क सदस्य हात हैं। यह 'अध्यक्षा वा सम्मेतन' सदन के अध्यक्ष की उसक काय, अधिवेदान बादि क सम्बव म सहायता करता है।

समोक्षा—फास की आयोग व्यवस्था के फलस्वरूप प्रत्यक विधेयक पर सामाय वाद विवाद हेतु सदन म 20 म 30 तक दम एव अनुमवी सदस्या का एक समूह सदय ही उपलब्ध रहता है जो पूणत मजग रहनर काय करता है। आयोग की बिंग अनुमति के विधेयक म काई नवीन सन्नोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। प्रस्तावित सन्तियान पर सामायत आयोग का मत लिया जाता है। आयोग द्वारा प्रस्तुत विध्यक के आधार होत है। यदि सदन विधेयक के आधार प्रति विद्याल की ही अस्थीकृत कर देता है तो आयोग द्वारा उस पर पुनिवचार होता है। विश्वा की ही अस्थीकृत कर देता है तो आयोग द्वारा उस पर पुनिवचार होता है। विश्वा की समस्त धाराओ पर विचार विभय होता है। विश्वा की समस्त धाराओ पर विचार विभय होता है। विश्वा की समस्त धाराओ पर विचार विभय होता है। विश्वा की समस्त धाराओ पर विचार विभय होता है। विश्वा की समस्त धाराओ पर विचार विभय होता हो। जायोग का अजन ने मांग (recommittal of the bill) हो जा सन्ती है। जायोग का अजन ने मांग (recommittal of the bill) हो जा सन्ति है। जायोग का अच्यक्ष या रेपोटियर (Rapporteur) सचोधन पर पुनिवचार में मांग कर सकता है। यदि कोई आयोग यह अगुमन करता है कि किसी विधेयक विणय पर जो किमी जय आयोग के विचाराधीन है, उसके द्वारा उपमुक्त विचार व्यक्त विचार सकता है तरसम्ब धी अपना प्रतिवेदन सदस्या म वितरित कर उत्तर है। स्वच्ट है कास य आयोगों का व्यापक विधारी दक्तिया प्राप्त हैं।

काइनर के अनुवार, 'आधागों की शिन्त एव प्रमाव दूराामी हैं। वे प्याव शिन्तवाली होते हैं और शासन के नेताआ तक का चुनौती देते रहते हैं। शासन पर प्रशासकीय एव भिन्नभण्डल द्वारा प्रस्तुत वजट पर नियायण के माध्यम द्वारा, न कि सामा य विधियको पर नियायण से उनके द्वारा शासन की नियमित किया जाता है। का साम प्रशिप्त की एर पिरतन त्योल समूहा के समुन्त मित्रभण्डल होते हैं। आधिक कर स इस परिस्थितिल य कम्माची से बचन के लिए आयोगा का विकास हुआ है। आयोगा के सदस्य विधि निर्माण के क्षेत्र म सस्यिय नेतत्व प्रयान करते हैं और उह स्थायिल एव निर तरता को प्रयान करते हैं जो अल्पकालीन मित्रभण्डल प्रयान कर स्थायिल एव निर तरता को प्रयान करते हैं जो अल्पकालीन मित्रभण्डल प्रयान कर स्थायिल एव निर तरता को प्रयान करते हैं जो अल्पकालीन मित्रभण्डल प्रयान की स्थाय अधी है। अयोग अपने स्थाय अधी है विशेषित जनके द्वारा विशेष योग्यता एव ज्ञान प्रयान किया जाता है और वे कमर स्थायों से सिन्य एव प्रयागवाली समुहों में मर्थाठत करते हैं। "

^{31 &#}x27;The power and influence of the Commissions are far reaching They have often become powerful enough to challenge the lead ership of the government, but their power has there been exted more through their powers of administrative control and through the annual challenge to the Cabinet Budget than an ordinary legislation The French ministries are awift changing coalitions.



सोवियत के सदस्य भी इस आयोग के नायों म नाग तेत हैं। इसरा तत्व सपनन राज्या के अधिकारा की वृद्धि बरना है। इस समिति ना नाय राष्ट्रीय वार्षिक पोनरां का विवसित करता एव सप गणराज्या की आधिक आवश्यकताओं को प्यान म रखना है। इस समिति के सुभावा के आधार पर सुप्रीम सावियत एवं सावियत रासन उरण विद्यालया, चिन्तात्वात, उच्च शिक्षा एव स्थानीय सावियत गृह व्यवस्था सम्बंधी प्रस्तावित विभाग योजगाता को स्थीनार दिया गया था।

समितिया एव आयोगा द्वारा सभी निषय सामा य बहुमत से लिप जात हैं।
समित या आयोग का कोई सदस्य यदि निषय से असहमत है ता उसे सन्वीचित प्रमिति
को अपने प्रस्ताय पृथक रूप से प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। सुप्रीम साधिवत
को अपने प्रस्ताय पृथक रूप से प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। सुप्रीम साधिवत
को अप यसस्या को आयोगा को बठका म माग लेने का अधिकार है पर दु वहाँ वे केतत
परामदा मर दे सकते हैं। प्रयत समितियाँ अपने कार्यों वे लिए उसी सदन के प्रति
उत्तरदायी होती ह जा उन्हें निवाचित करता है। सदन के समुद्रसाम कात म वे स्वर्
के अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होती है। आँग एव जिल्क के अनुसार सुप्रीम सोविवत
की वेदिक मामला, विधान एव वजट सम्याधी समितियाँ अस्यधिक महत्व की है।
सुप्रीम सोवियत का अधिवतन वप में केवल एक सप्ताह या दस दिन का होता है।
पूपी स्थिति म सोवियत रूस म सामितियाँ अमितियाँ समितिया से बही अधिक महत्वप्रम

भारत मे समिति-व्यवस्था

मारत म बिधि निर्माण समितिया का इतिहास बहुत पुराना है। 1853 ई के चाटर अधिनियम के अतमत विधान परिपद् की स्थापना 1854 ई म की गयी पी और उसी वप परिपद ने एक समिति का निर्माण किया था। तब स प्रत्येक मारतीय अधिक सारी बाद परिपद ने एक समिति का निर्माण किया था। तब स प्रत्येक मारतीय अध्यक्षिया हारा बिधि निर्माण काय म योग दने हेतु समितिया का निर्माण किया जाता रहा है। मारतीय विधि निर्माण समितियाँ ब्रिटिश समिति प्रणामी पर आधारित है। पराचु वोनों में एक महस्त्रपण अतर यह है कि भारतीय ससद में ग्रेट ब्रिटेन की माति सम्मूण सदन की समिति का अभाव है।

मारतीय संसद के दोना सदना में अनेक समितियाँ हैं। प्रस्ताबित विधेवक की समीक्षा के लिए समय समय पर मारतीय संसद म अलिरिक्त (Ad hoc) समितियाँ में स्थापना की जाती हैं। अल भारतीय संसद म दो प्रकार की समितिया है सायी समितिया (Standing Committees), एव अत्यायी समितिया (Ad hoc Committees)। अत्यायी समितिया के अत्यादा दोनो संदग्ते द्वारा समय समय पर नियुक्त की जान पाली समस्त प्रदर एव समुक्त समितिया आ जाती हैं। अत्यायो समितियाँ कियी वर्दिय वियोग नी पूर्ति के लिए गठित की जाती हैं और काय के समान्त हो जाने पर मग पर दी जाती है।

³² Ogg and Zmk Modern Foreign Governments, 1956, p 857

महत्वपूण विवेयका पर विचार हेतु दोनो सदनो द्वारा समुक्त समितियो का भी गठन किया जाता है। कभी-कभी गैर-विधायो मामलो पर विचार करने हेतु भी समुक्त समितिया काता है। कभी-कभी गैर-विधायो मामलो पर विचार करने हेतु भी समुक्त समितिया गठित की जाती हैं। उदाहरण के लिए, 1956 ई म द्वितीय पचवर्षीय योजना पर विचार हेतु एक समुक्त समिति का गठन किया गया था। माया आयोग के प्रतिवेदन पर विचार हेतु भी अस्यायी समुक्त समिति गठित की गयी थी। स्वामी समितिया का वर्गीकरण³, समितिया के कार्यों के आधार पर एस एस मीरे द्वारा विमा कर मुझ्तित किया गया है

- 1 अ वेपक समितिया (Committees to Enquire)
 - (1) आवेदन समिति (Committee of Petitions)
 - (ii) विशेषाधिकार समिति (Committee of Privileges)
 - 2 निरीक्षण समितिया (Committee of Scrutinize)
 - (I) शासकीय आश्वासन समिति (Committee of Government Assurances)

(11) अधीनस्य विधान समिति (Committee on Subordinate

- Legislation)
 3 सदन के काम से सम्बन्धित प्रदासकीय प्रकृति की समितिया (Committees of an Administrative Character Relating to the Business of the House)
 - (1) सदन के अधिवेशना ने सदस्यों की अनुपरियति सन्बंधी समिति (Committee on Absence of Members from the Sit-
 - tings of the House) (ii) कायक्रम शरामशदात्री समिति (Business Advisory Commit-
 - tec) (III) व्यक्तिगत-सदस्य विधेयक एव प्रस्ताव सम्ब^{न्}धी समिति (Commit-
 - tee on Private Members' Bills and Resolutions)
 - (iv) नियम समिति (Rules Committee)
 - सदस्या की मुविया एव व्यवस्या समिति (Committee dealing with Provision of Facilities to Members)
 - (i) सामा य उद्देश्य समिति (General Purposes Committee)
 - (11) सदन समिति (House Committee)
 - (iii) पुस्तकालय समिति (Library Committee)

³³ S S More 'Practice and Procedure of Indian Parliament', cited by A. C Kapur Select Constitutions (Indian Constitution), 1965, p 244

- (iv) समदीय मण्या व बात एवं मसा माबाधी प्रयुक्त पनिति (Joint Committee on Salares and Allowances of Members of Parliament)
- 5 विसीय मनिविषयी (Financial Committees)
 - (1) अनुमान मिर्मा (Lstimates Committee)

(u) मानवारि रमा ममिरि (Public Accounts Committee)

स्थायो समितियाँ (Standing Committees) भारतीय लागममा म निम्न स्थायो गमितियो हैं सावयनित नेपा समिति, अनुमान समिति तथा कायकम परामणात्रको, विषयाधिकार, निवस, आकृत् व्यक्तिगत-गदस्य विधेयर एव प्रस्ताव सम्बाधी मिनियो एव गामराय आस्तावनी तपा अधीनस्य विपान समितियौ । सावजी के सेसा समिति तथा अन्तिम दो समि तियां कायपालिका पर नियात्रण के त्रमायपूण सायन हैं। रोप मनी महितियां मन्त्र के आतरिक मामला स सम्बन्धित हैं।

राज्यममा म निम्न 6 स्थायी ममितियी हैं आयदन, विरोगाधिरार, निवन, सदन एवं सामान्य उद्दृत्य तथा कायत्रम परामग्रदात्री सम्बन्धि समितियाँ। प्रथम ^{बार} समितिया वे काय लाक्समा को समितिया व समान ही हैं। मदन एव सामा व रूप समितियां उन कार्यों का सम्यादित करती हैं जिनका सदन के कायत्रम से कोइ नम्ब नहीं होता। सदन समिति का राज्यसमा व आयास सम्बायी मामला स सम्बाय होता है। सामा य उद्देव्य समिति नायालय क आवास एवं ससदीय नागजा के प्रकारन जसे सामाय मामला स सम्बर्धित होती है। इन सभी समितिया नो राज्यसमा ह अध्यक्ष द्वारा मनानीत विया जाता है। यह समितियाँ नवीन समितिया क ाठन तक पदारुढ रहती हैं। राज्यसमा का अध्या नियम समिति एव कायकम परामनानवी समिति का पदन सदस्य होता है।

प्रवर समितियाँ (Select Committees) निसी विधेयन की जीन या अविषण या शिकायत पर विचार हतु प्रवर समिति की नियुक्ति की जाती है। प्रथम प्रवर समिति की स्थापना 1854 ई म हुई थी। इसके पश्चात हर विधानमण्डल म अनकानक प्रवर समितिया की स्थापना हाती रही है। दोनो सदनो मे प्रवर समितिया सम्ब धी नियम समान हैं। प्रवर समिति में विधेयक को भेजन का प्रस्ताव स्वीकार किये जान के पश्चात उसे प्रवर समिति को प्रेपित वर दिया जाता है। विधेयक को प्रस्तावित करन वाला सदस्य प्रवर समिति के सदस्यो के नामों का सुभाव देता है। प्रवर समिति म नियुक्त विये जाने कंपूब सदस्यों की इच्या नात कर ती जाती है। सदन का अध्यक्ष सदस्यों में से ही समिति के अध्यक्ष की नियुक्त करता है। यदि अध्यक्ष भी समिति का सदस्य होता है तो वह स्वय समिति की अध्यक्षता करता है। एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति मणपूर्ति के लिए आवस्यक होती है। निणय बहुमत से होते है। अध्यक्ष को विवाद की स्थिति में निणायक मत देने का अधिकार होता है। प्रवर समितिया उप-समितिया भी निमुक्त कर सकती है। इन सिमितिया के अधिकेशन गुप्त होते है। प्रवर समितिया और उनकी उप समितिया व्यमित्यों के अधिकेशन गुप्त होते है। प्रवर समितिया और उनकी उप समितिया व्यमित्यों को अपने समक्ष साक्ष्य देने अथवा कोई पन या कांगजात उपस्थित करने का आदेश दे सकती हैं। निश्चित अवधि के भीतर समिति अपना प्रतिवेदन सदन को प्रीपित करती है। निश्चित द्वारा यदि कोई समय निश्चित नहीं किया जाता है तो सुचना प्राप्त करने के एक माह के भीतर समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देना चाहिए। समिति के बहुमत के निणय से असहमत सदस्या को प्रयक्त कर देना चाहिए। समिति के बहुमत के निणय से असहमत सदस्या को प्रयक्त कर से अपना मत व्यक्त करने का अधिकार होता है। सिपित के अध्यक्ष को समिति के काय एव सगठन को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक निर्वेश देने का अधिकार होता है। जो मानी किसी समिति का सदस्य नहीं होता, उसे समिति के अध्यक्ष की अनुमति से समिति में अपने विचार व्यक्त करने की सुवधा होती है। जो सस्य सदस्य समिति के सदस्य मही होते, उहे समिति के अधिकार होता है। पर जु उह समिति के अधिवदाना म समिति से अग के रूप भी भाग लेने का अधिकार होता है। पर जु उह समिति के अधिवदाना म समिति के अग के रूप भी भाग लेने का अधिकार नहीं होती, है। सि

कुछ प्रमुख समितिया का विवरण निम्नवत् है

नियम समिति (Rules Committee)— नियम समिति का वायित्व सदन की काय पढति विषयक मामला की जाज करना होता है। वतमान काय-पढित के नियमों में आवश्यक संशोधन करने या नवीन नियम बनाने की सिफारिश समिति द्वारा ही की जाति है। लेक्सम वास्पीकर नियम समिति वा पदेन सदस्य होता है। उसकी असुपरिवर्ति म उपाध्यक्ष कथ्यक्षता करता है। इसकी सदस्य सस्या 15 है जो लोकसमा के स्पीकर पा राज्यक्षमा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जाते हैं।

विशेषाधिकार समिति (Committee on Privileges)—विशेषाधिकार समिति का सम्बन्ध सदन एव सदन के सबस्यों के विशेषाधिकारों तथा उनके भग होते से सम्बन्धित मामलों से होता है। इसकी सदस्य सरया 15 है जो सन के आरम्म म स्पीकर द्वारा मनोनीत किये जात है।

ध्यक्तिगत सबस्य विधेयक सिमित (Private Members' Bills Committee)---यह सिमित व्यक्तिगत सब्स्यो द्वारा प्रस्तावित विवेयकाया प्रस्तावा की परीक्षा करती है। सिमित द्वारा ऐसे विधेयक दो वर्गों म विमाजित कर दिये जात है और उनके लिए समय निश्चित कर दिया जाता है।

कायकम परामगोदारी समिति (Business Advisory Committee)—इस समिति द्वारा सदन वा कायत्रम निश्चित किया जाता है एव विभिन्न विधेयको के लिए समय निथारित किया जाता है। इनकी सदस्य-सम्बा 15 है। स्पीकर इस समिति वा अध्यक्ष होता है। 432 | आधुनिय दासनत त्र

सासकीय आस्पासन समिति (Committee on Government Assur ances)—स्पोक्ट के द्वारा एक वय में लिए 15 सदस्या की यह समिति गृंदिव की जाती है। यह मन्त्रिया द्वारा सदन म समय-गमय पर दिय गय वचना, आस्वास्ता एव निरुच्या की समीक्षा करती है और सदन को यह प्रतिवदन देती है कि उनम स दिन आस्वासना को नित्र्या चित्र विचा गमा है और आस्वासना नो निष्धित अविधि म शूर्य किया गया है या नहीं। इस समिति द्वारा इस बाल पर विदोध वस दिया गया है कि प्रत्येक मंत्री को अपने आस्वासना का दो साह की अवधि म पूरा कर देना वाहिए। यदि कोई संची इसम असक्य उहुता है तो उस सदन प इसका स्मप्टीकरण देना चाहिए। यह समिति पर्याख्य प्रभावसाली है।

अधीनस्य विधान समिति (Committee on Subordinate Legislation)— इस समिति का काय यह दलना है कि ससद द्वारा अधीनस्य विधान की जो धाँत्याँ विधि निर्माण हतु प्रदान को जाती हैं उनका सही रूप म प्रयोग किया जाता है बका नहीं। समिति सम्बन्धित सबन म प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं। सिमिति का धाँपर्त है कि वह यह देखे कि निमित अधीनस्य विधि सम्बन्धित ससदीय विधि के मृत उर्हों के अनुरूप है अथवा नहीं। सिमिति का 1 अध्यार एवं 15 सदस्य होते हैं, वो सीकर हारा एक वय के निए मनानीन विध जाते हैं। उसकी स्थापना 1953 ई म शैं गयी थी।

यह मिति अधीनस्य विधान के सन्य य म निम्नसिक्षित बातो की हनाहों करती है क्या अधीनस्य विधि ससदीम विधि के मूस मन्तव्या के अनुरूप है ? हो अधीनस्य विधान म कुछ ऐसी बाते हैं जिन्हें ससद द्वारा पृथक विधि के रूप म सीवार किया जाना चाहिए ?, क्या अधीनस्य विधान के रूप ने विधान के रूप ने विधान के रूप ने विधान के रूप में किया जाना चाहिए ?, क्या अधीनस्य विधि द्वारा को है नवीन कर प्रस्तावित किया गरी है ?, क्या ससदीम विधि द्वारा विणित विध्या के सम्याध में अधीनस्य विधि म की है विधान की एक क्या अधीनस्य विधि द्वारा सिक्त के दुरुपयाग की सम्मावत्त है ? इस समिति का काम सत्तीयजनक नहीं रहा है और न यह अपने काय को हैं निवंदा पात्ती है ! विधि आयोग ने एक स्थायी ममिति के निर्माण का सुभाव विमा माजिसके सदस्य पूरे समय के लिए नियुक्त हा बीरजी समी प्रस्त विधानों की ममीसा करें।

सावजिक लेखा समिति (Public Accounts Committee)—सावजिक लेखा समिति एव अनुमान समिति (Estimates Committee) ससद की वो महत्वपूर्ण समिति एव अनुमान समिति (Estimates Committee) ससद की वो महत्वपूर्ण समितियाँ हैं। मारत मे प्रथम सावजिकक लेखा समिति 1923 ई में के द्वीय विधान मण्डन द्वारा पिठित को यारी भी। नवीन सविधान के प्रारम्भ होने पर यह सिक्ति गरी वर्षों में मसदीय सिक्ति वर्गी है। सावजिक लेखा समिति का काम सदन द्वारा स्वीवृत्ति स्वारम्भ के स्थम एव लेखा, वाधिक विद्याप लेखा एक अय लेखा का परीक्षणकरता है। सिक्तिय लेखा एक अय लेखा का परीक्षणकरता है। सिक्तिय हेवलती है कि सदन द्वारा जा धन जिस मदम प्रथम करने की स्वीवृति प्रधान में। गरी है, वह उसी भव म प्यय निया गरा है या नहीं। इसकी सदस्य-सस्था 22 है।

निसम 7 सदस्य राज्यसमा के होते हैं। सदस्यमण समानुषातिक प्रतिनिधरव प्रणाली के आधार पर एक वप के लिए निवाचित किय जाते हैं। कोई मानी इस समिति का विधायी समिति व्यवस्था | 433 प्रदास नहीं होता है। वोकसमा के विष्ठतम गैर-सरकारी सदस्य को स्पीकर समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता है। सिमिति द्वारा राज्यों के निगमा, स्वायत एव अद्ध-त्वायत्त निकाया एव राष्ट्रपति के निर्देश पर नियानक एव महालेखाकार द्वारा किये गये परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन पर भी विचार किया जाता है। कामहोत्तर एव आडीटर निरत के वापिक प्रतिवेदन पर विचार करना समिति का प्रधान काम है। विस-नालय द्वारा विमामीय अपव्यय को रोकने के लिए निमित नियमा की परीक्षा भी यही समिनि करती है।

मीरित जो स (Morris Jones) ने समिति के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा है कि नावजनिक तेला समिति को तीन दिशाओं में सफलता प्राप्त हु है— (1) समिति ने प्रशासन के जन दोषों पर प्रकाश डाला है जि ह सरकार जागसक रहते हुए भी मुमारने म असफल रही है। (2) समिति एव ऑडीटर जनरल का अस्तित प्रशासन के लिए निर तर इस चेताबनी के रूप म है कि सदन द्वारा उनके कार्यों की जाच की जाती है। (3) समिति के द्वीय सरकारी अधिकारियो एव राजनीतिज्ञा की एक दूसर के समीप लाती है और अधिकारिया को लोकमत क प्रति सबग रहन तथा राजनीतिज्ञा को रचनात्मक आलोचना का प्रविस्तव प्रदान करती है।

अनुमान समिति (Estimates Committee)—मारत मे जनुमान समिति 1 की स्थापना अप्रैल 1950 ई म की गयी थी। 1953 ई म इसके दायित्वा में बढि की तथी। अनुमान समिति का काय सदन क समक्ष प्रस्तुत विभाग के यम के अनुमाना की मान करना है। यह महत्वपुण वायित्व है क्योंकि प्रत्येक विमान के अनुमानित स्वय सम्बन्धित विमागीय महिन्दुभ वाजाप हरणा । के अनुमानित स्वय सम्बन्धित विमागीय महिन्दा हारा तयार किये जाते हैं और विस म नी ब्रास उनको विस्तत जाच के परचात ही वे सदन में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किय माते हैं। विमागीय अनुमानित मानो म नीति सम्बन्धी प्रस्त निहित होते हैं। सदन होरा बहुमानित माम को आलोचना का अथ सासकीय नीति के प्रति सहस्व स देह भीय मागा को वर्गसा करक उस स्वयं को संजुद्ध कर तेना वाहिए वि भाग जिल्ला पर भागा पा पराक्षा करक वस स्वय का स तुन्द कर कमा भागवर मा भागवर के किया करके वस स्वय का स तुन्द कर कमा भागवर म को जन्म के और वह स्वीकृति प्रदान करना वासनीय है। इस प्रकार समिति भारत ह बाद उह स्वाकृति प्रदान करना वाधनाय है। २० नगार वाजात को अनुमानों की जान के माध्यम से शासन की नीति के सम्बंध म निचार व्यक्त भारतीय वास्त्र क्षांच्यम सं सास्त्र का गास के प्रस्तु के विश्व का गास के प्रस्तु के विश्व का गास के प्रस्तु के विश्व का गास के विश्व के किया है और समूच सासन समिति के सिनाधिकार में आ भारत है। अपना अध्य ही आता है और संबंध पायत वाताव के अवस्था आता है। सिमिति ने अनेक अवसरा पर सासकीय नीति के संयोधन एव परिवदन का प्रभाव दिया है। त्रितंत्रव निय नक एव प्रहातेकाकार श्री अधीक चरा ने भारतका ना अनुसान समिति के इस अधिकार को कायपासिका शक्ति का अविकाय माना है। ्रुवार धामात व ६६ आयवार का काववारका चारका राज्यावण्य वारा १ व समिति के संदर्भा होरा जाव हेतु देश के विसिन सामा का असम किया जाता है।

434 | आधुनिक दासनत त्र

अशोक चादा के मतानुसार इसस अनुशासनहीनता पनपती है। समिति न उन नार्यो को गरनास्वय प्रारम्भ कर दिया है जा कि मूल रूप म सदन के अधिकार-क्षत्र में आते हैं। अ यह सदन की एक स्थायी समिति है । इसकी उप-समितियाँ होती हैं। समिति की सदस्य मन्या 30 है जो लोरसना के सदस्या द्वारा समानुपातिक प्रति निधित्व प्रणाली ने आधार पर एक्ल सक्रमणीय मत क अनुनार निवासित क्यि वात हैं । इसम राज्यसमा का कोई सदस्य नहीं होता । समिति का अध्यक्ष स्पीकर द्वारा मनोनीत किया जाता है। सदस्या या कायकाल एक वप हाता है। अनुमान समिति का मुल्य उद्देश्य प्रशासन म मितव्ययता एव क्षमता लाना है। यदि समिति यह समन्त्री है कि यहुत साधन ध्यथ जा रहा है ता नीति के परिवतन पर बल द सकती है। समिति के प्रतिबदना म तीन प्रकार की सिफारिशें होती हैं (1) सगठन ने मुधार, (2) मितव्ययता, एव (3) अनुमानित मांगो का प्रस्तुत करन सम्बाधी सुमाव। अनु

मान समिति भारतीय प्रशासन की क्षमता के विकास म महत्वपूण योग दे रही है।

14

प्रदत्त विधान [DELEGATED LEGISLATION]

सभी देशों मे प्रदत्त विधान का विकास युद्धोत्तरकालीन प्रमुख विशेपता है, यद्यपि इसका उत्पत्ति सम्बाधी सिद्धात अति प्राचीन है। ¹ डायसी के जीवन-काल में ही प्रदत्त विधान को मा यता दी जाने लगी थी। ब्रिटेन म 1832 ई के सुआर अधिनियम एव स्थानीय जासन सम्बाधी उपनियम के फलस्वरूप प्रदत्त विधान या प्रशासकीय विधि में असाधारण विद्व हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के काल में प्रदत्त विधान का असम्मावित विकास हजा था एव सुरक्षा नियमो (Defence of the Realm Act, 1914 15) के अत्तगत कार्यपालिका को व्यापक शक्तिया प्रदान की गयी थी। विधानमण्डन द्वारा अपनी विधि निमाण शक्ति को कायपालिका एव उसके अधिकारिया की हस्ता तरित कर दिया जाता है और व ऐसे पारित अधिनियम के अधीन विभागीय अधिकारिया को बिबि निर्माण का अधिकार प्रदान कर देते है। इस प्रकार काय-पालिका द्वारा निर्मित विधि या नियम या आदेश प्रदत्त विधान (delegated legislation) क्हलाता है। यह आधृतिक विधान का अनिवाय अग है। विधि निर्माण काय-पालिका का काय नहीं है अपित विधानमण्डल का एकाधिकार है। विशेष परिस्थितिया या कारणवरा विधि वताकर उसकी सीमा के अत्तवत नियम बनान का अधिकार काय-पालिका को प्रदत्त कर दिया जाता है। जत प्रदत्त विधान विधानमण्डल द्वारा निर्मित विधि की तुलना में कायपालिका द्वारा निर्मित जधीनस्य विधान है। 'मित्रयों की शक्ति सम्बाधी समिति ने प्रदत्त विधान की परिभाषा देत हुए कहा है कि 'स्वय ससद द्वारा

¹ Lash, op cit, p 214 डी एल हीविट के अनुसार 1800 ई के पूब 30 वार व्यवस्मापिका द्वारा विधि का प्रवत्तीकरण हुआ था।

² प्रदत्त विधान को जधीनस्य (subordinate) विधान, द्वितीय (secondary) या विभागीय (departmental) या प्रसासकीय (administrative) विधि मी कहते हैं।

प्रदत्त साविधानिक सत्ता वे अधीन लघु विधान शक्ति का अधीनस्य अधिकारिया एव निकामा द्वारा प्रयोग प्रदत्त विधान है।" ब्रिटेन म 1890 ई म 168 एव 1913 र में 444 अधीनस्य नियम एव आदेश जारी किय गय थे। 1937 ई क परचात प्रतिवय 1500 में कम ऐसे नियमों का निर्माण नहीं हुआ है। 1945 ई म इनकी सन्या 1706 1951 ई म 1166 तथा 1952 म 706 थी। सयक्त राज्य अमेरिना म राष्ट्रपति थियोडार रूजवेल्ट ने 1011, विल्सन ने 1770, कुलिज न 1428, हूबर न 1424 एवं फ्रेकलिन रूजवेल्ट ने 3711 प्रशासकीय आदेश जारी किये थे। अय वर्ग म मो प्रशासकीय आदेशा की मध्या इनसे अधिक ही होगी।

प्रदत्त विधान का विकास

इसके विकास के निम्न कारण है

 (1) विधानमण्डल के कार्यों में राज्य के कायक्षेत्र म वृद्धि के साथ साथ वसा भारण विद्व हुई है। समयामाय के कारण विधानमण्डल अपने इन बढे हुए दायित्व को निमाने म प्राय असमथ रहते है। अत विधानमण्डतो द्वारा महस्वपूण विधेयका से सम्बन्धित प्रमुख सिद्धान्ता की परिमापा सम्बधित विधेयक म कर दी जाती है और उन सिद्धा तो के अधीन विदि एव नियम वनाने का दायित्व विभागीम कम चारिया को सीप दिया जाता है। फाइनर का मत है कि कोई भी विधानमण्डल सभी प्रकार की आवश्यक विधिया से सम्बर्धित नियमादि का निर्माण वपपप त 24 घटे लगातार काम करके भी पुरा नहीं कर सकता।

(2) इसके अतिरिक्त अनेक विधियों का सम्बंध जटिल एवं तकनीकी मानती से होता है, उदाहरणाथ, मशीन, औषधि, पशु-चिकित्सा आदि । विधानमण्डना के सदस्यों में इन विविधों के निर्माण के लिए अपक्षित योग्यता का अमान रहता है ॥ इस सम्बंध म उन्ह प्राविधिक एव वैनानिक विशेषकों क परामश एवं सहयोग नी

आवरयकता होती है।

(3) विधानमण्डल के सन या अधिवेशन सदैव नहीं होते रहते जबकि विभिन्न सामाजिक समस्याएँ तीव गति से उत्पन्न होती रहती है अत उनके एवं अप सकटकालीन समस्याओं के समावान हेत् एवं उहे हिट्ट में रखकर अवसर के अनुकूत आवश्यक विधि या नियम क निर्माण का अधिनार प्रशासकीय कमचारिया को प्र^{श्न} क्या जाना चाहिए।

(4) फाइनर न संयुक्त राज्य अमेरिकी काँग्रम का इम संदर्भ म उद्धरण देत

P 523

³ Delegated Legislation is defined 'as the exercise of minor legis lative power by subordinate authorities and bodies in pursuance of statutory authority given by the Parliament itself The com mittee on Ministers Power was appointed by British Lord Chan cellor in 1929 to examine the question of delegated legislation 4 Finer H The Theory and Practice of Modern Governments, 1956,

हुए कहा है कि कुछ विषयों में अमेरिको काग्नेस की हुटि अस्पट्ट होती है। उस यह स्पट्ट नहीं होता कि क्या करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ऐसे अनेक विषयों के सम्बाध में उनके महत्व के कारण काग्नेस नियम बनाने का अधिकार कायपालिका को सीपने के लिए भी तैयार नहीं होती। फलम्बरूप अमेरिकी काग्नेस न फाइनर के अनुसार प्रयोग के रूप में विधि निर्माण का दायित्व आयोगों जैसे सधीय व्यापार आयोग और अत-राज्यीय ब्यापार आयोग को सीप दिया है।

सक्षर में, ससद के पास समयामान, विधिया से सम्बन्धित विषयों की जिट-लता एवं प्राविधिक्ता, गम्मीर असम्मावित घटनाओं का चटित होना एवं सम्मावना तथा विधि निमाण में सरलता की आवश्यकता ने 20वीं सदी में प्रवत्त विधान की एक अनिवाय आवश्यकता बना दिया है।

कोई प्रशासकीय नियम यदि सम्बिष्धित मूल ससदीय अधिनियम की बाराआ के विपरीत होता है या प्रदत्त सत्ता का अधिकमण करता है तो ग्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकत है, अयथा यायालया को इन नियमों के संदम में हस्तक्षेप फरन का अधिकार नहीं होता है और वे ससदीय विधि की माति ही प्रभावकारी होते हैं।

विभिन्न देशों में प्रदत्त विधान

प्रेट ब्रिटेन

बिटिश प्रदत्त विधान पर ससद का निय यण होता है । महत्वपूण मामला सम्बाधी विमागीय नियमादि तमी बच माने जाते है जब कि ससद न उनको स्थीकृति प्रदान कर दो हो । मूल विधेयक म उल्लिखित रीति के अनुसार ससद को स्थीकृति सुत ऐसे समस्त नियमादि को उसके समस्र प्रस्तुत किया जाता ह । इनमें स कुछ विधिष्ट नियमा के सम्ब प म सबद की स्थीकृति अनिवायत आवश्यक होती है अयथा श्रंप समस्त नियमादि को समस्य प म सबद की स्थीकृति अनिवायत आवश्यक होती है अयथा श्रंप समस्त नियमादि ससद के समस्र एक निश्चित अवश्य तक प्रस्तुत रहने के परचात स्वत नियम या जात है तथा ससदीय विधि को माति ही प्रमावकारी होते हैं । कुछ नियम या आदश्य एस भी होते हैं जो ससद क समस्र विचार एव स्थीकृति वे लिए रख ता जाते हैं तथा ससदीय विधि को माति ही प्रमावकारी होते हैं । कुछ नियम या आदश्य एस भी होते हैं जो ससद क समस्र विचार एव स्थीकृति वे लिए रख ता जाते हैं तथा ससद को उनक सम्बाध म अकुछ करना नही यदता । कुछ कायपालन औरो मा तो ससद म मस्तुत वरने की भी आवस्यक्वा नही होती । सामाध्यत ऐसे आदेश मो ससदीय सदम में चालीस मायकारी दिना तक विचार हुत रखे रहना आयरवक होता है । पाइतर के अनुसार ममुक्त राज्य अगरिका एव फान्स में प्रदत्त विधान पर बिटन की भीति ससद का निया याच नही हाता है ।

प्रदत्त विधान का क्षेत्र व्यापक होता है और इनके अधीन प्राप्त दात्तियाँ मी व्यापक होती हैं। निस्स रह प्रदत्त विधानों म से बुद्ध केवल प्रपत्र, कागवात, जन-गणना एव तास्थिकों से मम्बिधत होते हैं। परातु सेव प्रदत्त या अधीन निवमा क्र----

⁵ Finer, H op at, p 524

द्वारा सम्बर्ियत विधि का क्रियान्वयन निर्वारित किया जाता है एव उनक द्वारा व्यक्तिगत स्वत त्रता या सम्पत्ति को निया त्रत किया जाता है। मानवीय त्रियाआ ना शासन द्वारा जितना अधिक नियोजन किया जायेगा उसी अनुपात म कायपालिका की शक्ति मे भी वृद्धि स्वामाविक होती है। " जब तक किसी प्रदत्त नियम का कि ही विश्वप आर्थिक या राजनीतिक हिता पर विपरीत प्रमाव नही पडता, ससद मे उन पर बहुवा कोई विचार नहीं किया जाता है। इसके कई कारण ह। व्यक्तिगत रूप म ससद के सदस्य इन नियमो एव आदेशा को चुनौती देने की क्षमता नही रखते और सदन क पास इनके हिलाय न तो आवश्यक समय है और न ही वाखित रुचि । विमागा द्वारा ऐसे नियम बनाने के पूज अनिवायत सम्बंधित पक्षो एव प्रतिनिधिया की परामध दायी समितियो से परामश एव विचार विमश किया जाता है। ऐसे नियमादि म से केवल कुछ पर ही ससद मे विचार होता है जिह कि यायालय द्वारा किसी विधिया सीमा के अतिनमण के कारण अवैध घोषित कर दिया जाता है। व्यक्तिगत विधयका से सम्बर्धित आदेशो के विरुद्ध जनता शिकायते कर सकती है। सावजनिक या 'गस कीय विधेयका के सम्बाध मे नीति या सिद्धात या मूल नियम के आधार पर जाव की आज्ञा दी जा सकती है। प्रशासकीय नियम या आदेश विमाग द्वारा निर्मित होते हैं। कभी कभी परामशदायी प्रतिनिधि सस्याओ से इन नियमो के सम्ब^{न्}ध म परामग्र^{जी} लिया जाता है । बहुघा ऐसे नियमा को ससद के अधिवेशन की समाप्ति के समय ही प्रता म स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। इन प्रदत्त विधियो पर वास्तविक जन प्रतिस्थि तमी ज्ञात होती है जब कि वे यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिये जाते हैं परन्तु ^{इस} समय तक पर्याप्त खच हो चुकता है। पर तु किसी नियस या आदेश के राजनिक औचित्य का परीक्षण कि व नियम जनता की स्वत नता को कहा तक प्रमाबित करत हं एवं उनकी क्या उपयोगिता है, किसी यायालय द्वारा भी सम्भव नहीं है। मित्रया की शक्ति सम्बाधी समिति ने अपने प्रतिवेदन म यह स्वीकार किया है कि मित्रयों की प्रदत्त शक्ति के निरीक्षण एव नियायण के लिए उपलब्ध शक्तियाँ अपर्याप्त हैं और इस बात का भय है कि कही सेवक स्वामी न बन जाय।7

बात को तथा है। के कहा सबक स्वामा ने बन जाया।

1914-16 ई में ब्रिटिस संसद द्वारा पारित मुरक्षा अधिनियमा ने मित्रम को मुद्र सचालन के लिए सभी कुछ करने की शक्तिया प्रशान कर दी थी। एक एमें विभेयक द्वारा म नी को न केवल आदेश देन अधितु अ य ऐस समस्त काय करने का भी अधिकार प्रशान किया गया था जिसे वह आवश्यक एव अधित समक्षे। यही नहीं उसे विभेयक के प्रावधानों म आवश्यकतानुसार संशोधन करने का भी अधिकार प्रशान किया गया था। 1931 ई की सकटकासीन स्थिति के निवारणाथ ससद द्वारा पारित हुँ की

6 Finer II op cil p 524

The Rating and Valuation Act, 1925

⁷ Committee of Ministers' Powers' Quoted by H Finer, p 525

विधियों की कभी को दूर करने के लिए सम्बन्धित मन्त्रिया को आदेश देन का अधिकार प्रदान किया गया था। 1932 ई म नगर-नियोजन अधिनियम के अन्तर्गत ब्रिटिश स्वास्य्य मन्त्री को स्थानीय अधिकारियों से परामश्च के पश्चात आवश्यक योजनाएँ वनाने का अधिकार दिया गया था। 1932 ई के कर-अविनियमों के अधीन टरिफ बोड (Tariff Board) को परिस्थितियों क अनुसार करों की दरे निवारित करने का अधिकार प्रदान किया गया था।

1929 ई मं गठित 'मिनयों की बिक्त सम्ब घो सिमिति' ने अपने प्रतिबेदन मं काम सं समा की एक स्वायी सिमिति के गठन की सिकारिश की यी। समी प्रशास कीय जादेशा को विधि बनने से पूच इस सिमित को प्रस्तावित किये जाने की व्यवस्था की गयी थी। सिमित का यह मी दायित्व निधीरित किया गया था कि किसी जादेश में यदि कोई कमी हो तो बहु इस सम्बाध मं सभा का घ्यान आकर्षित करें।

हितीय विश्व युद्धकाल में ग्रेट विटेन में प्रदत्त विधान में बढी वृद्धि हुई थी। इससे काम स सभा एवं जाय सावजनिक नेताओं को वडी विन्ता हुई। फलत मई 1949 ई म विधिक नियमा एवं आदेशो सम्बंधी एक प्रवर समिति का निर्माण किया गया। प्रत्येक सन म नवीन समिति गेटित की जाती है। 10 इस समिति के हारा प्रत्येक विधिक आदेश या नियम का परीक्षण किया जाता है। समिति ऐसे नियमा की तरफ सबन वा ध्यान धार्कपिक करती है जिनके हारा (1) सावजनिक राजस्व पर अितिस्त कर-मार पडता हो, (2) यायालय के समक्ष सम्बद्धित मामलों को चुनौती न दी जा सके, (3) अधिनियम हारा प्रदत्त शक्ति का अनुवित एवं अस्वामाविक उपन्योग किया जाये एवं (4) अधिनियम में एसं उपन क्ष हो जो अनावश्यक विसम्ब के कारण प्रकाशित न किये गयं हो, आदि।

इस समिति का कायमार अधिक है। इसने 1943-44 ई मे 1473 नियमो एव बादिया म स 291 का परीक्षण किया था। 1944-45 ई म 168 तथा 1945 46 ई म 469 प्रशासकीय आदेशा का परीक्षण किया गया। 1946 47 ई म 1900 नियमो म स 795 का परीक्षण हुआ या जिनम से नेवल 6 आदेशा की तरफ सदन का घ्यान आकरित किया गया था। 11 इस समिति द्वारा कांकसमा के सदस्यों को आवस्यक पूछताछ हुँत अपने समक्ष बुलाया जाता है। समिति द्वारा कांम स समा को अपना प्रतिवेदन दिया जाता है। पाइनर का मत है कि समय वीतने के साथ साथ समिति के द्वारा अधिक उचित पद्धित एव व्यवस्था की स्वापना की जायेगी एव वह सव जावस्यक जानवारी उपलब्ध हो सक्यों जिसस ससद प्रदत्त विधान पर अधिक

⁹ The Town Planning Act, 1932.

¹⁰ लाडसमा म 1925 ई म इसी प्रकार की एक समिति गठित की गयी थी।

¹¹ Finer, H op cut , p 525

प्रभावकारी नियापण कर समें 112 समिति न प्रतिवेदना पर विचार करने के लिए ससद के पास आवश्यक समय ना अमान है। प्रतिदिन ना काय समाप्त होन के बार केवल आधे पण्ट का समय प्रदत्त विधान पर विचार करन के लिए सदस्या को प्राप्त होता है। यह समय बहुत हो अपर्याप्त है। फारस

फार म दो प्रकार के प्रशासकीय नियमया आदेश प्रचित्तत हु (1) सागरणित्वन (Simple Rules), एव (2) प्रशासकीय नियम (Rules of Public Administration)। प्रवत्त विधान का अन्य आधुनिक राज्या की मीति कास म मी तीव गति वे विकास हुआ है। तृतीय गणराज्य के अतगत साधारण प्रवत्त नियम जारी करन के अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किया गया था। 13 चतुष्य गणराज्य के सिवान के हारा यह स्थित प्रधानमंत्री का प्रदान की गयी थी। 14 फाइनर की हिंद म वह परिवतन विधान्द प्रहर्श का है। 18 प्रवासकीय नियम वा निर्माण मन्तिनयका ब्राग किया जाता है और काजिस्स ऑफ स्टेट के समक्ष जह चुनीती थी जा सर्गों है। फाइनर का रूपन है कि तृतीय गणराज्य की सरकारा द्वारा विमिन्न यामना म, विषय कर वितीय मामनो से इन नियमा का व्यापक प्रयोग किया यथा था। ततीप व्यवस्था कर वित्यस स्था की अस्थिर सरकारा के लिए उत्तरदायी, विद्वाही एवं असहसो करों वाली मेज सत्तर के कारण प्रदत्त विधान का उपयोग अनिवाय सा हो गया था। स्वर्ध समुवत राज्य अमेरिका

समुक्त राज्य अमेरिका म भी प्रदत्त विधान की बिद्ध हुई हूं। स्मरणा है कि समुक्त राज्य अमेरिका की शासन पद्धित का आधार शक्ति पृथककरण है। इति स्वामाविक निष्कप यह है कि सिद्धा तत समुक्त राज्य म यस्तियों का प्रदर्शकरण असम्मव है। विधि निर्माण की शक्ति सविधान द्वारा काग्नेस में अधिन्तित की गर्वा है अति किसी जग्य सस्या या निकाम को उसका प्रदर्शकरण समेधानिक हरिट सं अधिक होया। सेकिन परिस्थितियों स वाध्य होकर इस साविधानिक किटनाई से वहने की प्रयास किया गर्या पर तु उससे केवल प्रक्तपूर्वक ही बचा जा सका है। कार्येस द्वारा अवद (quasi) विधि निर्माण शक्ति ही प्रयान की जाती है, न कि विधि निर्माण शिक्ष शिक्ष स्वाप साव सका है। वार्येस केवल प्रकार की जाती है, न कि विधि निर्माण शिक्ष स्वाप का सका है। वार्येस्ट्री

^{12 &}quot;As the time goes on, the Committee must assist the establish ment of more rational procedures and create a corpus of know ledge enabling better control —Finer H op at 1 p 525

¹³ Article 3 of the Constitutional Law of February 25, 1875

¹⁴ Article 47 of the Constitution of 1946

¹⁵ Finer, H op cit p 528 16 Finer H op cit, p 528

सर्वाच्च यायालय न भी इसे स्वीकार किया है। 1928 ई म एक मुक्दमें में सर्वोच्च यायालय द्वारा दिये गय निणय के अनुसार विधि निर्माण शक्ति का प्रदत्तीकरण निपिद्ध नहीं है। 12 अमेरिकी यायालय प्रदत्तीकरण के विरुद्ध नहीं है। पर जु ज होने सत्ता के प्रदत्तीकरण को सीमित करने का प्रयत्न किया है। अमेरिकी यायालय की हिए अबिक उसकी सीमा निर्धारित कर ने ता प्रयत्न किया है। अमेरिकी यायालय की हिए म सत्ता प्रदत्तीकरण तभी वैध माना जाना चाहिए अबिक उसकी सीमा निर्धारित कर दो गयी हो। उसे किसी भी अवस्था म अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। यह मत एक उदाहरण से अधिक स्वष्ट हो जाता है 1933 ई म राष्ट्रीय औद्योगिक पुनरत्यान अधिनियम की धारा 3 के अनुसार राष्ट्रपति को प्रतियोगिता से सन्यित्त जीवति सिहता को स्वीकृत वरने का अधिकार दिया गया था। सर्वाच्च यायालय ने इस प्रावधान को अवैध ठहराया। अपने निणय म सर्वोच्च यायालय ने यह मत ध्यक्त कि अधिनयम के अत्वात्त राष्ट्रपति को जो सत्ता प्रदान की गयी है वह असीमित है, अत अवैध है।

सपुन्त राज्य अमरिका म प्रवत्त विधान पर ब्रिटिश पद्धति के विपरीत विधान-मण्डल की अपेक्षा यावालयो का अधिक निय नण है। प्रशासन द्वारा निर्मित नियमो की समीक्षा काम्रेस द्वारा नहीं की जाती है। समी अधीनस्य या प्रवत्त नियमा, आदेशो एव जपनियमो को यावालय म चुनौती दी जा सकती है। सामायत यावालय निम्न आधारा पर प्रवत्त विधान का परीक्षण करते है

- क्या प्रशासकीय नियम सम्बन्धित मूल अधिनियम के अनुरूप हैं
- (2) क्या मूल अधिनियस म प्रस्तावित रीति के अनुसार ही उनका निर्माण किया गया है $^{\circ}$
- (3) क्या मूल अधिनियम वैधानिक है ? यदि मूल अधिनियम अवैधानिक है तो उस अधिनियम पर आधारित प्रशासकीय नियम उपनियम या आदेश स्वत ही अवैधानिक हो जाते हैं।
 - (4) वया नियम या जादेश सर्वैशामिक अधिकारा का अतिक्रमण करता है ^{२१०}

हुर क अनुसार अमरिकी यायालयो की दृष्टि म किसी प्रदत्त विधान की वेयता की निम्न आवश्यकताए हैं

- शक्ति का प्रदत्तीकरण करन वाली विदि स्वय वैधानिक हानी चाहिए अर्थात उसे काँग्रेस के अधिकार क्षेत्र म होना चाहिए।
- (2) प्रदत्तीकरण सीमित हाना चाहिए, अथात सत्ता के प्रदत्तीकरण ना विषय एव क्षेत्र सुस्पष्ट होना चाहिए ।

¹⁷ Hampton and Co vs U S, (S C) 1928

¹⁸ The National Industrial Recovery Act of 1933

¹⁹ Finer H op at , p 526

- (3) सत्ता का प्रदत्तीव रण सावजनिक अधिकारिया को हाना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति या व्यक्तिगत समया को ।
- (4) दण्ड निर्धारित करन की झक्ति को प्रदत्त नहीं किया जा सकता। प्रदत्त विधान के किसी नियम के उल्लघन के लिए जो दण्ड आवस्यक हो, कांग्रेस द्वारा स्वय उसको निर्धारित करना चाहिए।

स्पष्ट है कि अमेरिजी सर्वोच्च यायालय न प्रदत्त विधान की धारणा के सिवधान-सम्मत माना है। 1935 ई म दो मामला म सर्वोच्च यायालय न निरुच ही कुछ प्रशासनिक विधिया को अवैधानिक घाषित किया था परन्तु तत्पश्चात आज तक किसी भी प्रशासनिक विधिया को अवधानिक घोषित नही किया गया है। महुक राज्य अमेरिका म दिनेन की भौति प्रदत्त विधान से सम्बी धत ससदीय समितिया री व्यवस्था नहीं होती है। ह्वीधरे के अनुसार समुक्त राज्य अमेरिका म इतके अतिष्क अय सावधानिया वरती जाती है, जसे सता के प्रदत्तीकरण सम्ब वी विधि का ध्यानपूर्वक एव सज्यातपूर्वक निर्माण, नियमा को लागू करने के पूर्व सम्बधित पत्ती की बावा को स्थानपूर्वक सुनना एव यायालय हारा निय नण, जो सयुक्त राज्य अमेरिका म इगनगढ़ की अरोक्षा कहा कि ध्याल की वा को को साम की साम

भारत

मारत म भी ग्रेट ग्रिटेन एव अमेरिका की मांति व्यापक रूप म प्रवाहरिय विधिया का निमाण किया जाता है। मारत एव ग्रेट ब्रिटन में ससदीय प्रणाली है पर्षु भारतीय ससद जिटिवा ससद की माति सम्प्रमु नहीं है फलत भारत में ससदीय विध्यों सवैधानिक विधि हारा मर्यादित हैं। यदि भारतीय ससद द्वारा निर्मित कोई विधि सिविधान के किसी प्रावनान के विपरीत है तो उसे असवैधानिक घोषित किया जाता स्वामाविक है। निम्न तीन परिस्थितियों म भारत म प्रदत्त विधान को असवधानिक पोषित किया जाता स्वामाविक है। निम्न तीन परिस्थितियों म भारत म प्रदत्त विधान को असवधानिक पोषित किया जा स्व

(1) प्रत्यायोजन करन वाला अविनियम अवैधानिक हो ।

(2) प्रदत्त विधान सविधान का अतिक्रमण करता हो।

(3) प्रदत्त विधान अपने भूल विधान के उपव धा के प्रतिकूल हो। अक्टूबर 1962 ई मे सकटकालीन स्थिति की घोषणा होने पर भारत म सुरक्षा नियमो (Defence of India Rules) को जारी किया गया था। इनके अधीन कायपातिका को विधि निर्माण की व्यापक शक्तिया प्रदान की ययो है। मारत मंत्रदत

22 Ibid p 111

²⁰ Hart An Introduction to Administrative Law, p. 318 Quoted by Dr M P Sharma Public Administration in Theory and Practice, p. 318

²¹ Wheare, K C Legislatures, op cit p 110

विधान से सम्बिधित तीन महत्वपूण मुकट्टम सर्वाच्च न्यायासय के समस विचार हेतु आये हैं। व है कमदा दिल्ली विधि विधिनयम (1951) विवाद, हरीशकर वागला वनाम मध्यप्रदेश राज्य (1954) एव वस तलाल वगरह ननाम बम्बई राज्य (1961) विवाद। दिल्ली विधि अधिनियम (1951) से सम्बिध्त विवाद मे यायाधीशा का सामाय मत यह या कि विधि निर्माण काय की सारभूत या मूल वातें प्रदत्त या प्रत्यान्तित (delegate) नहीं की जा सकती। यही प्रत्यायाजन की सीमा है। उपरोक्त तीना विवादा म दिये यये निणया का सार यह है कि व्यवस्थापिका सामाजिक एव आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए विधियों का निर्माण करती है और वह अपनी इच्छा के व्यक्तियों को अधीनस्थ शक्ति निर्माण करती है और वह अपनी इच्छा के व्यक्तियों को अधीनस्थ शक्ति निर्माण करती है प्रत्याचयन के लिए सुविधाजनक समभती है, प्रत्याजित कर सकती है। लेकिन सर्वोच्च यायास्य का मत या कि व्यवस्थापिका किसी मी जबस्था में अपनी भूत विधि निर्माण सम्ब धी शक्ति को प्रवत्त नहीं कर सकती। उसे स्वय विधायों नीति एव उसके सिद्धा ता का निधारण करना जाहिए एव उक्त नीति के नियान्ययन के लिए सत्ता प्रवत्त करने के पूर्व वावश्यक निर्देश जी निर्धारित करने वाहिए। 12

प्रवत्त विधान पर सबदीय नियं नण हेतु 1953 ई मे एक समिति का निर्माण किया गया था। इसे अधीनस्य विधान समिति (Committee on Subordinate Legislation) की सज्ञा दी गयी है। इनकी स्थापना के पूव प्रक्रिया सम्बंधी नियमो (Rules of Procedures) के जात्मत प्रवत्त विधान सम्बंधी दो व्यवस्थाएँ—नियम 88 एव 222—थी। नियम 88 के अनुसार जिस विधेयक मे शक्ति के प्रत्यायोजन का प्रस्ताव किया जाता था उससे प्रस्ताव के सामा य एव असामा य स्वरूप एव उसके क्षेत्र को परिमाणित करने वाले एक स्मृति एव का होना आवश्यक होता था। नियम 222 के अमुसार सबदीय विधि प्रस्ताव के अधीन निर्मित सभी प्रशासकीय आदेश के सवन के समक्ष एव उनके सागु होने के पुत्र च इन्हें गुज्य मुक्तियुत्त करने को आवश्यक ता होती थी।

उक्त समिति का मुख्य काय यह देखना है कि कायपालिका द्वारा निर्मित नियम एवं विनियम या आदेश प्रत्याजित करने वाली मूल विधि के अनुकूल है या नहीं। समिति द्वारा निम्न आधारा पर किसी प्रदत्त विधि का परीक्षण किया जाता है ⁴⁴

- (1) प्रशासकीय नियम सम्बाधित मूल विधि में उल्लिखित सामा प उद्देश्या के अपून्त है या नहीं ?
- (2) विषय-वस्तु की दृष्टि से प्रस्तावित नियम म वे सब बातें हैं या नहीं, जो किसी ससदीय अधिनियम मे द्वोती चाहिए ?
 - (3) क्या प्रस्तावित नियम द्वारा कोई कर लगाया गया है ?
 - (4) क्या 'यायालया के अधिकार क्षेत्र म प्रस्तावित प्रशासकीय विधि वाधक है ?

²³ Delhi Laws Act etc AIR 151 S C 332

²⁴ Avasthı and Maheshwarı Public Administration 1971, p 449

(5) तथा प्रस्तावित जियम, किमी एस मामने म जिमक सम्बंध म मून अधिनियम अस्पट्ट है, पूर्वापक्षी काल स ही प्रमानी निया गया है ?

(6) सम्बाधित व्यय त्या सचित निधि या लाक राजस्व पर नार है या उन्ने

लिया गया है ? (7) क्या प्रस्तावित नियम द्वारा मूल विधेयक म प्रदत्त शक्तिया व अनु^{चि}

प्रयोग की आसरा है ?

(8) यथा प्रशासकीय नियम ने प्रशासन एवं उस ससद के समक्ष रखन म नतु चित विलम्ब किया गया है?

(9) यया किसी कारण प्रस्तावित प्रदत्त विधि क स्वरूप या अभिप्रा^{व क} स्पप्टीकरण की आवश्यकता है?

अधीनस्य विधान समिति ने 1953 ई से 1965 ई तक अपनी 65 बठकी म 8500 आदेशाकी जाँच की है एव 22 प्रतिवेदन प्रस्तुत किय हैं। समिति ^{के} प्रभावपूर्ण काय की प्रशासा मारिस जीन्स (Morris Jones) जस विद्वात न की है। उसके अनुसार समिति ने अपने महत्वपूर्ण काय का प्रारम्य योग्यता एव कमल्या ह किया है।

समिति न ससदीय नियातण को प्रभावशाली बनाने हुत अनक सुभाव^{निय है} जसे राजपत्र म प्रकाशित हान के पश्चात शीझ ही नियम सदन म विचार कहा रखा जाना चाहिए। सदन म प्रशासकीय विधिया अधिकतम 30 दिन तक रखी रही चाहिए एव सदन को नियमो म सदाधन ना पूण अधिकार होना चाहिए।

समिति द्वारा प्रदत्त विधान सम्बाधी कई व्यवस्थाओं की निदा की गयी है। उदाहरणाथ उनके द्वारा यायालयो के अधिकार-क्षेत्र को सीमित करना, मूल अधि नियम के उपबाधी का अतिक्रमण, अस्पट्ट शब्दावली एव प्रशासकीय विधि का सन्त म प्रस्तुत करने एव उनके प्रकाशन म अनुचित विलम्ब । समिति की अनेक सिंपारिं स्वीकार की जाचुकी हैं।25

प्रदत्त विधान की आलोचना

प्रदत्त विधान की तीव आलोचना की गयी है। लॉड होवट के ने ब्रिटन के प्र^{हत} विधान एवं प्रशासकीय यायालया की 'नवीन निरक्शत'न' (New Despoissm) नामक अपनी पुस्तक म तीव्र आलोचना की है। उहाने इह 'मुप्त एव घणित पड्डान' कहकर पुकारा है। लाड हीयट ने नौकरशाही की तीत्र आलोचना करत हुए कहा है कि अब वह उन शक्तियो का प्रयोग कर रही है जो अधिकाशत ससद और यायपालिश के अधिकार-क्षेत्र म आती है। रैमजे म्योर²⁷ न हीवट क तकों को वडी ही बुद्धिमता

²⁵ Refer to Avasthi and Maheshwari op at pp 450 451 26

They are 'dark and smister conspiracies' "-Lord Hewart 27 Refer to Ramsay Muir How Britain is Governed 1951 pp 45 49

पूबक समयन प्रदान किया है। 1931 ई म ऑक्सफोड विश्वविद्यालय क प्रसिद्ध विद्वान प्रो सी के ठलन द्वारा प्रकाशित अपनी पुस्तक 'विजयी नौकरसाही' (Bureaucracy Trumpham) मे प्रदक्त विधान की तीज आसोचना की गमी है।

रैसके म्योर के द्वारा प्रदत्त विधान की आलोचना के सादम म व्यक्त निम्म विचार महत्वपूण हैं ससदीय विधि के अधीन हाने के कारण प्रदत्त विधान द्वारा प्राप्त अधिकार। पर कायपालिका का एकाधिकार होता है। फलत 'मन्त्री का निणय अतिम हैं, मूल ससदीय विधि म एकी हो व्यवस्था होती है। अत कोई प्रायामय हस्तक्षेप नहीं रूर सकता। यह ठीक ह कि विभागीय अधिकारियो द्वारा प्रदत्त विधान के अत्तमत प्राप्त व्यापक चिक्त न वडी सनगता स उपभाग किया जाता है पर तु यह याय व स्थापित सिद्धात के सवधा विपरीत है कि वचाव का अवसर प्रदार्श किये विना ही किसी को कोर दण्ड दिया जाय। (प्रदत्त विधान द्वारा) नारिका को यायालय म अपीज के अधिकारियो का मत है। एसा कई प्रसिद्ध अधिकारिया का मत है। "

प्ररत्त विधान की आलोचना के प्रमुख आधार निम्न हैं

(1) प्रसासनीय अधिवारियों को विधि निर्माण को शक्ति देने के फलस्वरूप निरकुराता म बिद्ध को आजका है। लॉड होवट का यह तक या कि प्राचीन काल म निरकुराता का अर्थ सामन की सीनी शिक्तियां का कंद्रीकरण हुआ करता था। जनता की स्वत नेता की रक्षा हेतु सर्वधानिक ध्यवस्था में इनका पृथवकरण किया गया है। प्रदत्त विधान एव प्रसासकीय ग्राय की ध्यवस्था के विकास एव बिद्ध ने सामन की याक्तियों का वेद्रीकरण पुन कर दिया है एवं निरकुश्तत च को वल प्रदान किया है। प्रशासकीय अधिकारियां हारा प्रदत्त विधान के प्रयाग से नायित स्वत नता के अित-क्षासकीय अधिकारियां हारा प्रदत्त विधान के प्रयाग से नायित स्वत नता के अित-

(2) प्रदत्त विधान के विकास से विधानमण्डल क अपने वायित्वा के प्रति चवासों। हो जाने की सम्भावना है। वह केवन मुख्य सिद्धा तो का है। अधिनियम म जल्लेख करने सत्तुब्द हो जाती है।

(3) प्रत्येक प्रदत्त विधि का पूण निरीक्षण और नियायण निवास कठिन है और इस बात की अधिक सम्मावना है कि उनके द्वारा अपने अधिकार क्षेत्रका अतिक्रमण किया जाध ।

(4) प्रदत्त विधान के निमाण म असगठित सामा य जनता के विधारी का

29 Ramsay Mutt How Britain is Governed, 1951, p 48

²⁸ साब ही साथ देखिए मर सेसिल कार (Sir Ceal Carr) द्वारा जॉन इ कारसेल (John B Kersell) की पुस्तक Parliamentary Supervision of Delegated Legislation के निए लिखित आक्रयन । इसमे प्रदत्त विधान की आलाचना वा पूर्वामान मिलता है।

महत्त्व नहीं दिया जाता है। यह ठीक है कि सम्बाधित प्रवासकीय निकाया स दिर्घ निर्माण के समय पराधवा कर लिया जाता है लेकिन नियमा वा सम्बप्ध तो बक्त से होता है न कि प्रदासकीय एजेंसिया से। विधानपण्डल जनता का प्रतिनिधित की

है अत उसक द्वारा निर्मित चिपिया से ही जनता के हिता की रक्षा सम्मव है। (5) प्रदत्त विधिया द्वारा 'यायपालिका नी सक्तिया पर प्रतिसंघ तना दिव जाता है। इसका यह अथ है कि नागरिका को द्वासन के बतियमण स उर्हे क्ली

स्वत त्रता की रक्षा के मूल अस्त्र से हो वचित कर दिया गया है। (6) अधिकारिया का इंग्टिकोण केवल प्रशासकीय अधात एकाणी होता है।

(6) अधिकारिया का इंग्टिकोण केयल प्रशासकीय अयात एकागी हाती है अत प्रदत्त विधान द्वारा राजनीतिक इंग्टिकोण नी उपक्षा मुनिहर्वत है।

(7) नमनीयता प्रदत्त विधान की एक प्रमुख विद्येपता है। परतु गही उहनी सबसे बढ़ी कमजोरी भी प्रमाणित हो सकती है। नियमा में घीन्न परिवतनी के नाल अराजकता एवं अस्थिरता को अधिक सम्मावना हो सकती है। इसक अतिरिक्त प्रमाधन की उचित व्यवस्था वे अमाव म जनता प्रदत्त विधान के सन्दम म अनिंदन भी ही सवती है।

उपयोगिता

उपरोक्त आलोचना के होते हुए भी यह स्वीकृत मत है कि प्रदत्त दिवा री निविचत उपयोगिता है। उत्तवन अप्रत्यक्ष उत्स्वेख प्रदत्त विधान के विकास के काली के सदम में भी किया जा चुका है।

(1) प्रदत्त विधान के फलस्वरूप विधानमण्डल अतिरिक्त काय मार है वृष्ट

(1) प्रदत्त विधान के फतस्वरूप विधानमण्डल अतिरिक्त काय नार ते पूर्ण हो जाते है एव जह सहत्वपूर्ण नीतिया सम्बन्धी प्रश्नो एव सामान्य सिद्धान्तो वर प्रात केंद्रित करने का अवसर प्राप्त हो जाता है।

कीं द्रित करने का अवसर प्राप्त हो जाता है।

(2) आधुनिक समाज से सम्बाधित अनेक विधिया के सम्बाध म आवस्क तकनीकी एव बारीक तथ्यों के सम्बाध में विधानमण्डल की अपक्षा विशेषकों क्रार्य

अभिक सुलक्षा हुआ परामक स्वयं प मावधानण्यत्य वा जरणा विश्व अभिक सुलक्षा हुआ परामक स्वयं सकता है। (3) विधि के निया वयन से प्रत्यक्षत अधिकारीगण सम्बर्धित होते हैं। बर्त किसी नीति एव विधि के निया वयन से उत्पन्नसमस्याओ एव कठिनाइयाकी विद्यानगण्ड द्वारा कल्पना भी नहीं की जा सकती और न उसका वाद्धित समाधान ही प्रस्तुत किया ब

सकता है। अतः नियम-निर्माण सम्ब घी शक्ति प्रशासकीय अधिकारिया को प्रदान करती सवया उचित है। (4) ससदीय विधियो की अपेक्षा प्रशासकीय नियमो को अनुमव से तार्ग

उठाते हुए अधिक सरलतापूचक पारित एवं सशोधित करना सम्भव होता है।
(5) प्रशासकीय नियम के निर्माण में सम्बन्धित पक्षा से सरलता एवं सुविधी
पूवक परामश्र किया जा सकता है।

ार्याच क्या जा सकता ह । (6) युद्ध, महामारी, प्राकृतिक प्रकोप आदि जसे सकट-वाल म सफतता के लिए यह वाछतीय है कि कायपालिका को आवश्यक विधि-निर्माण की शक्ति प्रदान की जाम । नियोजन एव विकास-कार्यों सम्ब घी नियमों का मी शीधतापुवक निर्माण सम्मव होता है ।

प्रस्त विधान के दोयों के वावजूद मो यह स्वीकाय है कि आधुनिक काल में
प्रधासन द्वारा नियमा का निर्माण आवस्यक एव अनिवाय है । 'मित्रयों की शक्ति
सम्बन्धी समिति' के अनुसार, "सत्य तो यह है कि यदि ससद अपनी विधि निर्माण शक्ति
के प्रदासिकरण के लिए तैयार नहीं होती है तो वह आधुनिक जनमत के इच्छाकूक् आवस्यक एव व्यापक माता म विधि निर्माण नहीं कर सकती।" व्यक्ति निर्माल निर्माल निर्माल नाति अप देशा के म दम म भी पूजत सत्य है। अब उपरोक्त समिति की हिन्द में
"प्रदत्त विधान कुछ विशेष उद्देशों के लिए निर्मिष्त एव उचित सीमा और रक्षाव्यवस्या के अपीन सवैधानिक हिन्द से बाखतीय है।"

प्रदत्त विधान के दोपों के निवारणार्थं प्रस्तावित उपाय निम्नलिखित है

- (1) ससद द्वारा विधि निमाण यक्ति का प्रवस्तीकरण अस्पट्ट नहीं होना चाहिए अपितु क्षेत्र व शक्ति की सुनिश्चित सीमा होनी चाहिए अपित कि आवस्यकता के अनुसार उनकी समीक्षा की जा सके एव नियायण रखा सके । ब्रिटेन म ससद सम्प्रमु है। अत प्रवस्त विधान पर बहा कोई यायिक नियायण नहीं है। सपुक्त राज्य अमिरिका ने "मामालया द्वारा प्रवस्त विधान पर सीमा निर्वारित की गयी है। बोतोमूर (Donosbusore) समिति ने अपने प्रतिवेदन म कहा था कि जिटिश समद द्वारा विधि निर्माण को जो शक्ति प्रशासकीय अधिकारिया वो प्रदान की जाती है उसकी स्पन्ट सीमाएँ निर्धारित होनी चाहिए। 50 सिमित का यह मत समी देगों के मादम मे सरस है।
 - (2) ससद या विभानमण्डल को कि ही सामाय उद्देश्यो हेतु ही विधि निर्माण की प्रांक्ति प्रशासन को प्रदान करनी चाहिए। असामाय एव असाधारण उद्देश्या जैसे, मराधान, सिद्धा को के सन्वय म विधि निर्माण, ससदीम विधि म सदीधन एव परि-वदन मा अपरामा की व्यास्था एव उनके लिए दण्ड प्रस्तावित करने के सम्बाय मे सामायत (ordinarily) विधि निर्माण शक्ति प्रदत्त नहीं को जानी चाहिए। उद्देशिय मामना म प्रशासन नो विधि निर्माण की व्यक्ति प्रदान की जानी है वहीं अनिवायत उत्तक्त काल । या २ वप तक सीयित कर देना चाहिए एव ससद को विधियन प्रदत्त विधिया को स्वीकृत करना चाहिए एव उनकी विशेष जाम की व्यवस्था परानी चाहिए।

The Committee on Ministers' Powers (Dononghmore Committee)
 Report, 1929, p 32
 Ibid, p 31

³⁾ Ibid p 63

(3) प्रदत्त विधान को निर्माण के पूच एव पहचार प्रकाशित किया जाना चाहिए एव सम्बिधित पद्धों से आवश्यक परामश्च नी व्यवस्था होनी चाहिए। ब्रिटेन में 1893 ई के नियम प्रकाशन अधिनियम के अधीन इन विधिया के पूच प्रकाशन की व्यवस्था थी। वाद म भी प्रदत्त विधान प्रकाशित पिया जाता है। सपुत्त राज्य अमेरिका म सभी सधीय नियम, अधिनियम एव गादेश, सधीय प्रजीपरण पुरितका अधिनियम, 1935 (Federal Register Act, 1935) के अधीन प्रकाशित किय जात है। प्रदल विधि के पारित होने के पहचात प्रकाशन की व्यवस्था 1946 ई के कायेत के एक अधिनियम होरा की यथी है। भारत में इस स दम से काई सदीय विधि नहीं है।

संयुक्त राज्य अवेरिका में सभी प्रदत्त विधाना की सार्वजनिक सुनवाह हाती है पर तु भारत एव ब्रिटन में ऐसी कोई ब्यवस्था नहीं है। केवस सम्बर्धित विशिष्ट पशा

से ही परामश की व्यवस्था है।

(4) विधानमण्डल द्वारा प्रत्यक प्रदत्त विधान वी ससदीय समीक्षा (parlia mentary scrutiny) की जानी चाहिए । बिटिय समद निम्न तरीको से प्रदत्त विधान की समीक्षा करती है । प्रत्यक मूल अधिनियम म सम्बिधत प्रशासकीय निवमा की समीक्षा का उल्लेख होता है

(1) समद के किसी निर्देश की आवश्यकता के अभाव म सम्बर्धित प्रदत्तियम

को मसद के विचाराथ प्रस्तुत करने की व्यवस्था है।

(11) ससद म विचाराथ प्रस्तुत प्रशासकीय नियमा के सम्बाध म एक निश्चित अवधि के अव्यन् दोनों में से किसी भी सदन में विपरीत प्रस्ताय द्वारा सम्बाधित विधि की समान्ति की मांग की जा सकती है।

(111) प्रवस्त विधान के अ तमत निर्मित नियमा को ससल हे समस दोना स्वर्गों या काम स सभा की एफट स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक होता है अयथा वे प्रमावकारी नहीं हा सकते। इस हा सकारात्मक प्रस्ताव पढाति (altismative resolution procedure) कहते हैं।

(1) प्रदत्त विधान का प्रारूप एवं निश्चित समय तक ससद के समक्ष रखी

रहना चाहिए ।

पह देशा गया है कि ग्रेट ब्रिटेन में "सकारात्मक प्रस्ताव व्यवस्था' के अभाव म सकड़ा विधयक समदीय निरीक्षण के विना ही पारित हो जाते हैं। सदस्यों को ब्रह्मिक कोमभार एक व्यक्ताता के कारण उनकी समीक्षा ना अवसर नहीं प्राप्त होता। अत प्रमामकीय नियमां को सदन के समझ प्रस्तुत करने (laying before the parisament) की व्यवस्था केवल एक औरचारिकता वन चुकी है। क्तत 1944 ई म प्रदत्त विधान सम्बन्धी एक प्रयूप सिमित की स्थापना की गयी।

त्रिटिश ससद को प्रशासकीय नियमा का रचल स्वीकार या अस्वीकार करने

ना अधिकार है। उस सबोधन की कोई ब्राक्ति प्राप्त नही है। यदि किसी प्रदत्त विधि में सजोधन करना आवश्यक होता है तो विधि निर्माण की प्रत्रिया का अनुगमन करना पडता है और ऐसी अवश्या म प्रदत्त विधान का नोई मूल्य नहीं रह जायेगा।

मारत म प्रदत्त विधान पर ससदीय नियाजण एव समीक्षा ग्रेट त्रिटेन की तुलना म अत्यधिक अविकसित अवस्था म है। अधिकाशत भूत ससदीय विधियों में सम्बिप्त प्रशासनीय नियमों को ससद के समक्ष प्रस्तुत करने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। जिन विधिया म ऐसी स्थवस्था होती भी ह तो उसके अनुसार एक निश्चत अवधि अर्थात् 14 दिन स 2 माह नक प्रशासनीय नियम ससद के समक्ष प्रस्तुत कर दिय जाते है। यदि इस अविध म ससद इनम कोई सशोधन या परिवज्जन नहीं करती अबधि समान्त होने के पश्चात वे प्रशासनीय हो वाते है। यहुत कम मामनों में 'सबारासक प्रस्ताव को पढाति' हा अनुयमन किया जाता है। यहुत कम मामनों में 'सबारासक प्रस्ताव को पढाति' हा अनुयमन किया जाता है।

समुक्त राज्य अमेरिका म प्रदक्त विधान पर नियायण का अधिकाश काय यापालया द्वारा किया जाता है। वहा कायस के समक्ष प्रस्तुत करने एव काग्रेस द्वारा समीक्षा को कोई ध्यवस्था नहीं है। ग्रेट प्रिटेन एक सारतीय समदो को माति अमेरिकी काग्रस को अपनी कोई प्रगासकीय विश्वित सम्ब धी समिति नहीं है अपितु काग्रस की विभिन्न समितिया ही यह काग्र करती है। काग्रेस प्ररत्त विधान को जनस्थल रीति स ही नियम्तित करती है। Administrative Procedures Act, 1946 अमेरिकी काग्रेस का इसी प्रकार का एक प्रयस्त है। राष्ट्रपति के पुनगठन सस्य वी आवेशों के बारे म यह व्यवस्था है कि वे काग्रेस के समझ 60 दिन की अवित तक के लिए प्रस्तुत कियं को ने वाहिए। स्पट है कि प्रशासकीय नियमों को अमेरिकी कांग्रेस के समझ प्रस्तुत करना कोई अनोशी वात नहीं है पर तु प्रशासकीय विध पर इस व्यवस्था है कारण काग्रेस का प्रस्था नियन्त वहत ही कम है।

(5) यायालयो द्वारा प्रवत्त विधान की समीक्षा (judicial review) की जानी चाहिए। यह देखना यायालयो का काय है कि प्रशासकीय अधिकारी प्रवत्त चिक्त के लेनाधिकार का अतिनमण नहीं करता है। विटेन एव सयुक्त राज्य नमें रिक्त में यायालयो द्वारा प्रवत्त विधान को सामा यत इसी आधार पर न्वैधानिक घोषित किया जाता है। पर तु दानो देशा म एक अ तर है। विटेन म ससद को किसी भी प्रवत्त विधि का यायिक नियानण स मुक्त करन वा पूण अधिकार है। लेकिन अमेरिकी कौमस की यह अधिकार प्राप्त नहीं है। मारत मे ग्रेट क्रिटेन एव समुक्त राज्य अमेरिका के मध्य की स्थिति है। ग्रेट क्रिटेन म किसी प्रवत्त विधान की वैधा निकता के लिए कचल यह अधीकार है कि उसे भूत विधि के अनुकूल होना चाहिए। विकान मारत व समुक्त राज्य अमेरिका म प्रवत्त विधान की वधानिकता (intra vires) की से केसीटिया हं (1) मूल निधान, एव (2) सविधान के अनुकूल होना। महिटेन म मूल प्रवत्त विधान यायिक वुनर्रीहाण के अत्रत्त नहीं आता है असिपु उसके अधीन

450 | आधुनिक शासनसात्र

निमित प्रशासकीय नियमो एव आदेशो की ही समीक्षा करने का अधिनार केवल न्याया लया नो होता है। स्मरणीय है कि मसदीय समोक्षा एव पायिक निरीक्षणका उद्देश्य प्रशासनिक अधिकारिया की स्वेच्छाचारिता को नियातित एव प्रतिविधित करना है।

प्रदत्त विधान के सिद्धान्त का शनै शनै विरोध कम हो रहा है तथा लोक त नीय पद्धति का यह एक आवश्यक अग वन गया है । प्रशासकीय व्यावहारिकता एव अनुभव ने उसको आवश्यकता एव महत्व पर अधिकाधिक वल दिया है। हरबंद मोरोसन³³ के अनुसार प्रदत्त निधान सिद्धा तत ठीक है लेकिन ससद को हर अवस्था मे उम पर सजग इण्टि रखनी चाहिए। लास्की ने भी प्रदत्त विधान की सालांचना का स्वीकार नहीं किया है। उनका मत है कि इस बात के साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि नियम निर्माण की जा शक्ति विभागों को प्रदान की गयी उसका उनके हारा दुह पयोग किया गया है। प्रदत्त विधान के विकास का विरोध उसकी गम्मीर समीक्षा के फलम्बल्प निष्प्रमानी हो जाता है एव ससदीय नियानण होने के कारण प्रदत्त विधान सकारात्मक राज्य के हेतु अनिवायत एव मूलत एक पद्धतिमूलक व्यवस्था है।

Herbert Morrison, Government and Parliament 1954, p 151 33

The protest against the growth of the delegated legislation collapses as soon as it is submitted to serious scrutiny (and) that 34 achieved, the system of delegated legislation is in fact, an elementary procedural convenience, essential to the positive state -Laski Parliamentary Government m England, 1952, pp 350 51

15

प्रत्यक्ष विधि-निर्माण [DIRECT LEGISLATION]

आधनिक लोकतात्रीय राज्या में विधि निर्माण का काय जनता के निर्वाचित

प्रतिनिधियो द्वारा सम्पादित किया जाता है। इसे प्रतिनिधि लोकतात्र कहते हं। राज्यो के विशाल क्षेत्रफल एव जनसंख्या के कारण जनता द्वारा प्रत्यक्षत विधि निमाण सम्भव नहीं है। लेकिन कुछ देशा म 'प्रत्यक्ष लाक्त न' के अवशेष आज भी विद्यमान हैं और वहा जनता प्रत्यक्षत विधि निर्माण से सम्बर्धित है। जनमत संग्रह (Referendum), अभिक्रम (Initiative) एव प्रत्यावतन (Recall), य तीन तरीके हैं जिनके द्वारा जनता स्वत विधि-निर्माण से भाग लेती है। स्टाग के अनुसार इनके प्रयोग के द्वारा विधानमण्डल के कार्यो एव कुछ मामला म विधायको के कायकाल को सीमित कर दिया गया ह । विधानमण्डल पर य व्यवस्थाएँ जनता का प्रत्यक्ष निय नण ह । प्रत्यक्ष विधि निर्माण के दो आधार है-प्रथम सैद्वातिक तथा द्वितीय व्यावहारिक । सैद्वातिक आधार के अनुसार जनता सम्पूण शक्ति का स्रोत है अत उसे प्रत्यक्षत विधि निर्माण करना चाहिए। द्वितीयत व्यावहारिक अनुभव के अनुसार जनेक मामलो म विधान मण्डलो के कार्यों एव विधिया से तीव निराशा हुई है। विधानमण्डल के कार्यों की समीक्षा के अभाव एव उनके हस्तक्षेप के विना विधि-निर्माण ने प्रत्यक्षत जनता द्वारा विधियों के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया है। अनेक राज्या म कठोर दलीय अनुशासन के कारण व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व पूणरूपेण नष्ट हो गया है। फाइनर के अनुसार प्रतिनिधित्व की कठिनाइयों के कारण जनेक बाता के साथ-साथ यह माग भी उठ खडी हुई कि ससदीय एव दलीय सरकारों की शक्तियों को जनता की प्रत्यक्ष काय-

^{&#}x27;Referendum के लिए हिंदी म जनमत सम्रह एव लोकमत सम्रह तथा
'Initiative' के लिए उपत्रम अभिक्रम एव प्रस्तावाधिकार राज्द प्रचलित हैं।
लेखक ने इनके लिए त्रमश जनमत सम्रह एव अभित्रम शब्दा का प्रयोग दिया है।

Strong, C F Modern Political Constitutions, 1963, p 222

वाही के द्वारा यदि समाप्त नहीं तो कम अवश्य किया जाना चाहिए।3 अत पाइनर के मतानुसार प्रत्यक्ष विधि निर्माण प्रतिनिधित्व की कठिनाई का परिणाम है।

जनमत मग्रह एव अभित्रम प्रत्यावतन (Recall) की तुलना म अपेक्षाकृत एक नग्म तरीका है। इसके अतिरिक्त नगर समा (Town meeting) प्रत्यक्ष प्रजात व का एक अप तरीका है। नगर समाएँ संयुक्त राज्य अमेरिका के पू इगलण्ड म प्रचिति हे । इनम सभी मतदाता एक साथ नगर अधिकाश्या को चुनते है एव स्थानीय मामलो को निर्णीत करते है। स्विटजरलण्ड के कम जनसरया वाले कैण्टना म लैण्डमजीमिडे (Landsgemends) की त्रथा है । इसम कण्टन की पूरा जनता शासन काव में वप में एक बार भाग लेती है, आवश्यक विधियों का निमाण करती है एवं पदाधिकारियों की चनती है। यहा प्रत्यक्ष प्रजातान के प्रचलित होने के कारण जनमत-सप्रह का व्यवहारत कोई मुल्य नहीं है।

प्रत्यक्ष विधि निर्माण के पक्ष में निम्न तक प्रस्तुत किये जाते है

(1) जनता स्वय विधि बनाती है अत उसके जनहित विरोधी होने की कोई आशका नहीं है। प्रतिनिधि प्राय अपन व्यक्तिगत एव वगगत स्वायों के अधीन विधि निर्माण कर सकत ह । प्रत्यक्ष विधि निर्माण म ऐसी कोई सम्मावना नहीं होती, न कोई विवि अन्यमत से पारित हो सकती है और न जनता पर कोई ऐसी विधि तादी ही जा सकती है जिसे वह नहीं चाहती हा ।

(2) प्रत्यक्ष विधि निर्माण के फलस्वरूप जनता मे राजनीतिक जागति एवं उत्तर दापित्व की भावना का विकास होता है।

(3) प्रत्यक्ष प्रणाली के अ तगत राजनीतिक दला का महत्व भी कम हो जाता है। अतिम निणय जनता के हाथों में होता है अत दलवादी व उससे उत्पान होने वाली युराइया बहुत कम हो जाती है।

(4) जनता द्वारा विधि निर्माण के कारण किसी विधि के विरुद्ध आ दोनन एव

विद्रोह की प्राय कोई सम्मावना नहीं रहती है। (5) स्वनिमित विधियो ना जनता द्वारा अधिक ईमानदारी से पालन दिया जाता है।

(6) शासन म भ्रष्टाचार भी कम हो जाता है।

स्ट्राम क मतानुसार जनमत-सम्रह, अभित्रम एव प्रत्यावर्तन (Recall) म निम्न गुण हैं

(1) भ्रष्ट एव जन आदेशो ना उल्लंघन नरने वाले विधानमण्डल के दोषा की जनमत संप्रह द्वारा संघारा जाता है।

³ Fmer H op at p 560

⁴ Strong C F op at, pp 229 230

- (2) निर्वाचका एव निर्वाचिता म अपक्षाकृत स्वस्थ एव लामदायक सम्ब ध स्यापित हो जाते है।
 - (3) जन मावना विरोधी विधि पारित नहीं हो पाती है।
- (4) अभिक्षम के द्वारा निर्वाचका का अपनी इच्छानुसार विधि निर्माणके प्रस्ताव स्वय प्रस्तावित करने के अवसर प्राप्त होत है।
- (5) प्रत्यावतन के अधिकार के प्रयोग से जनता द्वारा निर्वाचित भ्रष्ट एव अनुत्तरदायी अधिकारिया को वाषस जुलाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

फाइनर⁵ के अनुसार प्रत्यक्ष प्रणाली के गुणो का आधार आधुनिक ससदीय प्रणालियों के वास्त्रविक एवं काल्यनिक दोष है।

- (1) ससद की भा तरिक फूट एव किनाइया से उत्पान दोषा को प्रत्यक्ष विधितिर्माण द्वारा दूर किया जाता है । विधानमण्डला म दली एव समूही म बहुधा अनुचित
 गठव भनो के फलस्वरूप सयोगवरा मिथित दली को बहुमत प्राप्त हो जाता है । ऐसी
 स्थित ने वाद्यित विधियां का निर्माण रूक जाता है वा वगगत विधियाँ राहण ही सर
 लतापूवक निर्मित होन लगती ह । सक्षेप म अनेक अवसरा पर ससदीय दलीय व्यवस्था
 सामा य इच्छा को अगिन्यक्त करने म असफल रहती है। सामा य इच्छा को पुनजीवित करन का एकमात्र उपयोग यही है कि प्रस्तावा को प्रत्यक्षत जनता क निणय
 के लिए प्रस्तुत किया जाय । उपराक्त तक 1919 ई की जयन सविधान समा मे
 पणक्रिण पिलाक्षित हए थे।
- " (2) प्रत्यक्ष विधि निर्माण का उपयोग आस्ट्रेलिया के सविशन की माति दोनो सदनों के मध्य उत्पन्न विवादा को हल करन के लिए भी किया जाता है।
- (3) समानुपालिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को निष्किय बनान वाले अच्छे या बुरे प्रमास को दूर करने हेत प्रत्यक्ष विधि निर्माण का प्रयोग क्यिग जाता है।
- (4) अनुवारवादिया का यह मत है कि सामा यत जनता अनुवार होती है जत प्रत्यक्ष विजि-निमाण जनकी हष्टि मे प्रयतिशील में होकर अनुवार होता है। जनता द्वारा अधिकाश्चत प्रयतिशील विश्वेयकों को स्वीकार नहीं किया जाता है।

जनमत संग्रह

प्रत्यक्ष विधि निर्माण के तरीको भ जनमत् सम्रह (Referendum) का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। जनमत् सम्रह के भाष्यम से जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधिया द्वारा प्रस्तावित अधिनियमा की उनक विधि वनन के पूज समीक्षा करती है तथा स्वय प्रत्यक्षत विधानमण्डल द्वारा पार्टित अधिनियम के सम्ब घ मे अपना मत सती है। सजनता द्वारा किसी अधिनियम को स्वीकार किये जान पर ही वह विधि वनता है

⁵ Finer, H op sit p 560

⁶ चकीस्लोबाकिया एव लूपानिया म जनम्त सग्रह के द्वारा कायपालिका एव व्यव स्थापिका म उत्पन विवादो के सम्बन्ध मे अतिम निषय किया जाता है।

जयमा अधिनियम समाप्त हो जाता है। जनमत संग्रह के द्वारा फाइनर के राव्दा म, जनता को अपन हो निवाचित प्रतिनिधियो द्वारा निर्मित किसी अधिनियम के बारे म अतिम निणयं का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ⁷ अत जनमत-संप्रह जनता क हाया मे निषेघाधिकार (veto) है जिससे विधानमण्डल के कार्यों को वह अस्वीकृत कर सकती है। स्ट्राम के अनुसार जनमत सग्रह को मत-सग्रह (Plebiscite) के नाम से भी जाना जाता है। इसका इतिहास अनुमानत अधिक प्राचीन है। रामन गणत नीय काल मे 'Plebiscitum' से तात्पय प्लीब्स की समिति द्वारा पारित विधेयक स होता था। इससे आधुनिक फ्रेंच शब्द Plebiscite' का 'जनता से अपील करने सम्बंधी' अय स्पष्ट होता है। 'मत सग्रह' शब्द का प्रयोग कुछ समय से त्याग दिया गया है और उसके स्थान पर जनमत संग्रह का प्रयोग अधिक प्रचलित हो गया है। 'जनमत सग्रह' शब्द का प्रयोग नेपोलियन प्रयम एव नेपोलियन तलीय द्वारा नी किया गया था। जनमत-सग्रह के द्वारा ही 1848 ई मे नेपोलियन ततीय सवप्रथम राप्ट्रपति चुना गया था तथा 1851 ई में गणतान के विरुद्ध विद्रोह की स्वीकृति भी वह पर्च जनता से जनमत सग्रह के माध्यम से ही प्राप्त कर सका था। 1851 इ म गणत प्रका अत हो गया और द्वितीय साम्राज्य का 1852 ई म उदय हुआ। जनमत-सप्रह का इसी प्रकार का दुरपयोग हिटलर ने जमनी म सत्ता म जान के लिए किया था। अपने राजनीतिक कार्यों के लिए उसने अनेक बार जनमत सग्रह कराय थे । नवस्वर 1933 ई म उसन जनमत-सग्रह द्वारा ही जमनी के राप्ट्र सथ की सदस्यता त्यागन पर जनता की स्वीकृति प्राप्त की थी। अप्रैल 1934 ई मे हिटलर द्वारा प्रधानम वी तथा राष्ट्रपति दोना पदो को सयुक्त करने पर जनमत-सग्रह वे माध्यम संही जनता न अपनी स्वीकृति दी थो। 1938 ई मे जमनी एव आस्ट्रिया के एकीकरण का जमन एव आस्ट्रियन जनता ने जनमत सग्रह द्वारा ही समयन किया था।

इसमें प्रश्न 1859 ई म इटली के एनीकरण और 1905 ई म स्वीटन के नींचें स पृथक होन पर जनमत सम्रह हुआ था। प्रथम विदय-युद क परचात अनग अव सरा पर जामत-सम्रह ना प्रयोग अनेक राष्ट्र जातिया के स्वमाग्य निणय (self deter mination) के हेलु निया गया। परन्तु जनमत सम्रह मूल उद्देश अर्थात अस्पतस्वर्ग भी समस्या का ममाधान एव लागतन्त्र नी रक्षा वा माग प्रयस्त न कर सका।

स्ट्राम न उपमुक्त सभी उदाहरण मत सबह (Plebscite) क लिए दिव है। Plebscite (मत-सबह) एव Referendum (जनमत सबह) म लखन प मतानुगर जार है, यर्चाप इतिहास क एक गुग म दोना का समानामी घाणा कर हम म प्रवाप दुना है। मत गबह (Plebscite) मा सम्बंध समाज की तिसी विदासक राज भीनिक मस्या म होता है और जनता उत्तर पृथ मा विषय म मत देती है, जब वि जामन-मचह (Referendum) क माध्यम स जनता विधानमण्य हारा गारित विधि

⁷ Finer, H op cut, p 560

या सर्वधानिक सरोधन को स्वीकृत या अर्स्वाकृत करती है। स्मरणीय है कि दोनो ही इस सिद्धात पर आधारित हैं कि जनता सम्प्रमु होती है।

अनेक सविधानों में जनमत संग्रह की व्यवस्था है । इसका उपयोग जनता द्वारा सबैधानिक संबोधन और विधियां की स्वीकृति के लिए किया जाता है। जनमत संग्रह दो प्रकार का होता है अनिवाय एव वकत्पिक। यह भी सम्भवहै कि कुछ मामलो में अनिवाय (compulsory) ता दूसरा म वकल्पिक (optional) जनमत सग्रह की व्यवस्था हो । आस्ट्रेलिया, डेनमांक, आयर, फास, इटली स्विटजरलैण्ड एव सयुक्त राज्य अमेरिका, के अरेक राज्यों म तथा अत्यात व्यवस्थित रूप में सवधानिक संशोधनों के सम्बाध मा यूजीलैण्ड मे जनमत सग्रह की व्यवस्था है। आस्ट्रेलिया एव प्यूजीलण्ड म आधुनिक शताब्दी म जनमत सग्रह का बहुत कम प्रयोग किया गया है। 1947 ई क इटली के गणत त्रीय सविधान की धारा 75 हारा 5 लाख मतवाताओं या 5 क्षेत्रीय समितिया के माग किय जाने पर किसी भी विधि को पुण या जाशिक रूप से जस्वीकृत करने के लिए जनमत सब्रह की व्यवस्था की गयी है। फास के पाचवे गणत त्रीय सर्विधान (1958 ई) के अधीन अनेक प्रतिवाधी सहित जनमत-सग्रह की व्यवस्था की गयी है। मेच सर्विधान म यह व्यवस्था है कि ससद के सत्रकाल म शासन या शासकीय पित्रका मे प्रकाश्चित दोनो सदना के संयुक्त प्रस्ताव के माध्यम से प्रस्ताव करने पर राष्ट्रपति किसी भी विशेषक पर जिसका शासकीय अधिकारियो के पुनगठन अथवा समाज के किसी सविधान विरोधी समसौते या सिध की स्वीकृति से सम्बाध हा, जनमत सग्रह ले सकता है। वस्युक्त राज्य अमेरिका म संघीय मामला में जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं है। लेकिन अनेक राज्यों म आधुनिक काल मे जनमत-सग्रह अमित्रम एव प्रत्यावतन की अपनाया गया है। ऑरे-गन कोलोरेडो, केलीफोर्निया और मेसेच्यूसटस मे जनमत सग्रह की व्यवस्था है । 5 से 10 प्रतिशत मतदाताओं का किसी भी विधि के सादम में जनमत-सग्रह की माग करने का अधिकार है। विधानमण्डल जिन विधियों को आवश्यकीय घोषित कर देत है, उन पर स्विटजरलैण्ड की भाति जनमत सग्रह की आवश्यकता नहीं है।

अभिक्रम

अभिकृत (Inttative) के अतगत जनता को अपनी इच्छा की विधिया विधानमण्डल से पारित करने की माग करने एव उन्ह प्रस्तावित करन का अवसर प्राप्त होता है। जनमत सम्रह जनता के हाथों में यदि नकारात्मक अस्त है तो अभि-कम सकारात्मक है। स्ट्राण की हिन्द में अभिनम जनगत सम्रह की तुलना में अधिक विकित्तत करमा है। अनगत सम्रह विधानमण्डल के दोषा से जनता की रक्षा करता है तो अभिकम विधानमण्डल के मूल रूपी दोषी का उपचार है। अभिकम स पक्ष म

⁸ Strong C F op cat, 1963, pp 225 226

यह तक प्रस्तुत किया जाता है कि विधानमण्डल जनमत का पूरी तरह प्रतिनिधित्व नहीं करते और जनमत सग्रह का सम्ब थ केवल विधानमण्डल द्वारा पारित विधियां से होता है, अत विधानमण्डल द्वारा शक्ति के दुरुपयोग के विषद्ध जनमत-सग्रह प्वाप्त प्रतिभूति नहीं है। जनमत-सग्रह एवा अभिक्रम दोना साथ-साथ काय करत है। जनता द्वारा प्रस्तावित विधिया विधानमण्डल द्वारा पारित होने पर पुन जनता के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत को जाती हैं। स्टाग के अनुस्त किसी मी दश म जिनक्ष का अस्त्रित्व जनमत सग्रह के विवास सम्भव हो नहीं है।

स्विटजरलण्ड एव संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्यों में अभिक्रम की व्यवस्था है। जमन म बीमर सिवधान एव इयोपिया के अत्ययत भी अमिक्रम की व्यवस्था थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के 19 राज्यों में विधि के सन्दर्भ म तथा 14 राज्यों में सवधानिक सदोधनों के तम्ब यम अभिक्रम प्रचलित है। जमन के बीमर दिधान के अनुसार 1/10 मतदाताओं द्वारा किसी विधेयक को प्रस्तावित करने की मींग करने पर रीस्टाग में उक्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता था और यदि रीस्टाग विधेयक को पारित कर देता या तो वह विधि वन जाता था, पर तु रीस्टाग द्वारा अधिनियम को अस्वीद्वृत किया जाने की अवस्था म उस पर जनमत सम्ब अभिवाय व्यवस्था थी। इटली क गणत त्रीय सविधान म भी अभिनम सम्ब धी ऐसी ही व्यवस्था थी। इटली क गणत त्रीय सविधान म भी अभिनम सम्ब धी ही व्यवस्था है।

प्रत्यावर्तन

स्ट्राग¹⁰ क अगुसार जन प्रतिनिधिया या निवाचित अधिकारियों को अपने पह से वापस बुलान अथात प्रत्यावतन की शक्ति या अधिकार कोई नवीन व्यवस्था नहीं है। प्रत्यावतन के अधोन प्रस्ट, अयोग प्रस्ट, अयोग पर तहक जन प्रतिनिधियों एव निवीचित अधिकारियों को जनता निश्चित सक्या म इस्ताक्षर करके उन्ह उनके पर से च्युत करन या इस्ते की शक्ति तहस्या म इस्ताक्षर करके उन्ह उनके पर से च्युत करन या इस्ते की सिक्त रखती है। फा स की राज्य अगित काल म फेब विधानमण्डल के अयोग सदस्यों को निर्वाचका हारा पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा गया या पर तु उनका यह प्रस्ताव स्वीइत नहीं हुआ था। आधुनिक काल म समुक्त राज्य अगेरिका के इस्ताय प्रत्याम प्रत्यावतन में जनमत सम्ह एवं अभिनम में प्रत्यावतन मी जनमत सम्ह एवं अभिनम में प्रत्यावतन मी जनमत सम्ह एवं अभिनम माति अधिकाशत पहिचा अशेरिकी राज्यों म ही अविक्र प्रयावति है। मुख राज्या म प्रत्यावतन की व्यवस्था विधा माण्डल एवं वायपातिका के सदस्या के अविविक्त यायाधीशा के सन्धम म भी प्रचलित है। कोलोरेडो राज्य म तो प्याव अशित कहार प्रयाविक ने प्रत्यावत का इतना व्यापक प्रयाव नहीं किया नया है। से स्वावत है। हिंदा नया विधा में अपवित्त है। कोलोरेडो राज्य म तो प्राया का स्वावत के स्वर्म म मी इस्ता प्रयाव प्रयाव म तो प्राया होता है। स्वाप के अनुसार कियों मी अय बहा म प्रत्यावतन का इतना व्यापक प्रयाव नहीं किया नया है। से सिचियत स्वरं के प्रयावत के मूल स्वविद्या म इस्ता व्यवस्था हात हुए भी

⁹ Strong C F op at, p 227

¹⁰ Ibid, pp 228-229

सोवियत मप क स्टालिन सविधान (1936 ई) म इसको स्थान नही दिया गया है। स्विटजरलैण्ड के सात केण्टना म जनता को निर्धारित बहुमत से केण्टना के विधान-मण्डलो के विधटन एव पुनर्निर्वाचन की माग विधानमण्डल के काय-काल के मध्य मे ही करने का अधिकार है।¹¹

प्रत्यावतन के अधिकार स निस्म देह मतदावाओं को कुछ अधिकार प्राप्त हो जात है। मेनिन इस अधिकार के अधीन राजनीतिक पदय न की भी काफी गुजाइश रहती है। चुनावा म पराजित प्रतिनिधि अपने विरोधी को अपदस्य करने के लिए आवश्यक संस्था म मतदाताओं के हस्तावर कराकर प्रत्यावतन के लिए आवश्यक नावेदन पर दिलवाने का प्रयन्त कर सकते हैं।

स्विट्जरलैण्ड मे जनमत संग्रह एव अभिकम¹

स्विट्जरलण्ड प्रस्थक्ष प्रजात न का देव है। स्विस राजनीतिक "यवस्था की यह सर्वाधिक महत्वपूष विशेषता है। जनमत-सग्रह एव अभिकम का सबसे अधिक सफ स्वापूषक प्रयोग स्विटजरलेण्ड म ही हुआ है। इनके माध्यम से जनता विधि निमाण म प्रत्यक्षत माग क्षेत्रे म समय हुई है और इसी कारण स्विस जनता का मुतीय सदन कहा जाता है।

जनमत सग्रह

स्विद्यलरलण्ड में जनमत-सप्रह दो प्रकार का है—जिनवाय, एवं वकल्पिक । 18 स्वित्त संधीय सविधान में संधोतन के लिए अनिवाय जनमत सप्रह की व्यवस्था है। 1921 ई फें सवैधानिक संधोधन के अधीन अनिविद्य काल या 15 व्यप से अधिक समय ने लिए की गयी अत्यरिष्ट्रीय सिध्या कं सम्ब घ में यदि 30 हजार नानिरिको एवं 8 केण्टना द्वारा जनमत सप्रह की मांग की जाती है ता जनमत मप्रह आवश्यन होता है। केण्टना के सभी सवगीनिक संधोवनों के सदम म अनिवायत जनमत सप्रह की व्यवस्था है। 8 केण्टना म सावारण विधि के सम्ब ध म मी अनिवाय जनमत सप्रह की व्यवस्था है। 8 केण्टना म सावारण विधि के सम्ब ध म मी अनिवाय जनमत सप्रह की व्यवस्था है। 16 केण्टना म प्रधासन एवं वित्त सम्ब धी मांमला न ही जनमत सप्रह को लिखान है। 16 केण्टना म प्रधासन एवं वित्त सम्ब धी मांमला न ही जनमत सप्रह को विधान है। 16 केण्टना म जनमत सप्रह की कोई स्थवस्या नहीं है। स्वित्त सधीय सविधान के अत्यत्य वक्तियक जनमत सप्रह की मांग 30 हजार मतदासाओं या 8 केण्टन दोता है। कि पारित होने के 90 दिन के भीतर की जा सकती हो। देव किल्पक जनमत-सप्रह की मांग सम्मवत सकट-कालीन या सकती हो। वैकिल्पक जनमत-सप्रह की मांग सम्मवत सकट-कालीन या अस्थारी प्रहार्त की विधियों के सम्ब घ म की जाती है यद्यि सभी प्रकार

¹¹ Strong C F op at, p 229

¹² इसके अतिरिक्त देखिए अध्याय 3।

¹³ स्ट्राग ने वकल्पिक (optional) जनमत सग्रह के लिए Faculative' शब्द का मी प्रयोग किया है !—Strong, C F op cut, p 226

की विधिया में सम्याध म जनमत सग्रह की माग वरन का अधिकार जनता का प्राप्त है। अत जनमत-सग्रह सामा य प्रकृति की विधिया के सम्याध म ही हो सकता है। वाधिक वजट, प्रशासकीय प्रकृति की निष्या के सम्याध म स्वि हो सकता है। वाधिक वजट, प्रशासकीय प्रकृति के निष्या पि सिंध्या के सम्याध म जनमत-सग्रह नहीं लिया जा सकता। संधीय विधानमण्डल जिन विधिया का आवर्षकीय (urgent) घोषित कर देता है उन पर भी जनमत-सग्रह नहीं होता है। अधिकाश कण्टना म अस्थायी प्रकृति की विधियाँ जनमत सग्रह के लिए प्रचारित नहीं की जाती हैं। कुछ केण्टना म जनमत सग्रह म अनिवाद मतदान का विधान है, जो मतदाता मतनान नहीं करता उसे दिण्डत किया जाता है। सवैधानिक संधीधन सम्याधी जनमत-सग्रह म के देनो एक मतदाताओं दोना वा हो बहुमत आवश्यक होता है लिक साधारण विधियों के सम्याध म किसी एक का अर्थात केण्टना या मतदाताओं का निर्वेध सम्बाधित होता के सम्याध म किसी एक का अर्थात केण्टना या मतदाताओं का निर्वेध सम्बाधित होता है।

अभिकम (Initiative) भी दो प्रकार का होता है—िर्मित (Formulated), एव अनिर्मित (Unformulated) । निर्मित अभिनम्म के अन्तरत जनता विधि का प्रारूप वमाकर विधानमण्डल की स्वीकृति के लिए प्रेपित करती है । ऐसी दशा म विधान मण्डल का यह दायित्व होता है कि वह उसे मूल रूप म पारित करे। अनिर्मित उप नम के अधीन जनता विधि के सामा य सिद्धाता एव उद्देश्या का उल्लेख मान करके विधानमण्डल से तस्तमन्व भी विधि वनाने की मौन करती है एव विधानमण्डल का यह कत्व्य है कि वह उन विद्धातों के आधार पर एव उद्देश्या के अनुरूप विधि का निर्माण करे तथा विचार विमल के परचात उसे पारित करे।

स्विटजरसण्ड के सधीय सविधान में अमिकस का प्रयोगसवधानिक विधिक तिए ही निवा जाता है। 50 हजार स्विस नागरिक सधीय सविधान के पूण सशोधन की मार्ग कर सकते हैं। आदिक स्वधानिक सबोधन के सम्ब में निमित एवं अनिमित अनि कम की व्यवस्था है। पूण एवं आधिक सवधानिक सदीयेना ने जनता एवं केण्टना के स्वार्थ होता है। केण्टना में दोना, सवैधानिक स्वधानिक सदायेना ने जनता एवं केण्टना के स्वप्त होता आवश्यक होता है। केण्टना में दोना, सवैधानिक एवं साधारण विधियों, के सदम में अभिन्म की व्यवस्था है। नागरिकों की निर्वारित सर्या द्वारा केण्टना के निर्वार्थ के पूण या आधिक सशोधन की मार्ग की जा सकती है। जेनेवा (Geneva) का केण्टन इसका अपवाद है। वहीं प्रति 15 वयं बाद सविधान मंतिवायत संबोधन होता है। तीन केण्टनों को छोड़कर रोप सभी केण्टना मंतानित (Geneva) को निर्वर्थ तोनी केण्टनों को छोड़कर रोप सभी केण्टनों मंतागरिका की निर्वर्थ तस्था की निर्वित या अनिर्वर्थ कर प्रवित्य सभी केण्टना मंतागरिका की निर्वर्थ तस्था को निर्वर्थ ता विविधा कर प्रसाव करने का अधिकार प्राप्त है। प्रस्तावित निर्वर्थ अधिनयम जनता के समक्ष मतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तावित अपिनियम जनता के समक्ष मतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। प्रसावित अपिनियम जनता के समक्ष मतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। प्रसावित अपिनियम जनता के समक्ष मतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। प्रसावित अपिनियम जनता के समक्ष मतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। स्तावित अपिनियम जनता के समक्ष मतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। स्तावित अपिनियम जनता के समक्ष मतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। स्तावित अपिनियम जनता के समक्ष मतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। स्तावित अपिनियम जनता के साथ प्रसावित विधाता की साथ प्रसाव में अनुमित प्राप्त के साथ स्वार्य के स्वार्य के साथ स्वर्य के साथ प्रसावित विधाता है। स्वर्य का निर्माण किया जाय या

नहीं। जनता द्वारा स्वीकृति देने पर विधि का निमाण कर एव उस पारित करके विधानमण्डल उस पर पुन जनमत समृह लेता है और जनता द्वारा इस वार भी स्वीकृत प्रत्यक्ष विधि निर्माण | 459 क्यि जान पर वह विधि वन जाता है।

समोक्षा—सामा यत जनमत सम्रह एव अभित्रम की व्यवस्या साय-साय होती है पर तु यह अनिवाय नहीं है। एक दूसर से पृथक भी इनका अस्तित होता है। स्तिटजरत्नषड इसका प्रमाण है। वहाँ इनका प्रारम्म एक साथ ही समस्त केण्टना म नहीं हुआ है। गाल (Gall) नामक कण्टन म 1931 ई म, बले (Bale) म 1832 ई म, बालेस (Valais) म 1839 ई म एव लूसरने (Lucerne) म 1841 ई म जनमत-सग्रह प्रारम्म हुआ था। अधिकास केण्टना का जनमत-सग्रह की ब्यवस्था को स्वीकार करने म करीब 30 वय का समय लगा था। 1848 ई एव 1874 ई के संविधाना म सवधानिक विधिया के लिए अनिवाय जनमत संग्रह की व्यवस्था थी पर तु हामा य विधियों के लिए वकल्पिक जनमत संग्रह का प्रारम्भ 1874 ई म हुआ था।

जनमत-तम्बह एव अभित्रम् म आधारमूत अत्तर है। जनता विधानमण्डल की विधिया पर जनमत-सम्रह हारा निषेधाधिकार का प्रयोग करती है। इसके विष रीत, अमित्रम के माध्यम से जनता को अपनी इच्छा की विधियों को प्रस्तावित करने के अवसर प्राप्त ही जात है। अंत जनमत संग्रह एक बाल की तरह है जिसके बारा जनता विधानमण्डल द्वारा निर्मित अवाद्यनीय विधिया ते अपनी रक्षा करती है और अभिकृत एक लडग की माति है जिसस वह अपने विचारो एव आवश्यकताओं के अनुकृत विधिया के निर्माण के लिए मान प्रशस्त करने म सफल होती है।

प्रत्यक्ष विधान की प्रणाली स्विटजरलैण्ड म असाधारण रूप से सफल रही है शीर जनमत संग्रह तथा अभिनम स्विस राजनीतिक व्यवस्या के स्थायी अग वन गये है।

(1) स्विस जनता का दीघनालीन स्वशासन का अनुमव जस्त्रप्ट देशमक्ति एक सामाजिक एकता की मानना तथा सानजितक दायित्व के प्रति अनुराग इसके उत्त कारण हैं। लॉड बाइस क अनुसार स्विटजरसँग्ड प्रत्यक्ष प्रजात न के लिए जबर भूमि है। "पीघो की माति सहयाएँ भी उपगुक्त भूमि एवं सूच के प्रकाश म ही फलती कुलतो है। उरी में लण्डसजीमि डे लोकप्रिय है। ज्यूरिल म जनमत सग्रह का प्रचलन हैं। दोना को ही यदि मिल्ल (Egypt) म रोपा जाय तो क्या वे सफल हो सकेंगे ?" निहचय ही नहीं 116 बाइस का यह कथन स्विटनरत्वण्ड एव प्रत्यक्ष प्रजात न के सदम मे प्रणत सत्य है। दूसरे देसा म प्रत्यक्ष प्रणात न की असफलता का मुख्य कारण यह है के बहुत का बाताबरण इन सस्याओं के विकास की ट्रिटि से सवया मिन है अर्थात

In Switzerland it is a natural growth racy of the soil There an owniecriang it is a natural growth racy of the son face institutions which, like plants flourish only on their own hillside and under their own sunshine. Bryce Modern Demo cractes Vol I 1929, pp 453 454

460 | जाधुनिक शासनतात्र

सामाय वातावरण एव शूमि इस प्रकार की सस्याक्षा के विकास क लिए उपयुक्त नहीं है।

(2) स्विस नागरिक स्वत प्रता प्रिय हैं। व स्वत प्रतापूवन मतदान करते हैं उनमे मावनाओं या उद्रेक नहीं होता। व विवेक को प्रमुखता देत हैं। काट्यनिक होने की अपेक्षा वे विवेकशील अधिक है। अधिकादात य शिक्षित हात हैं। फरत प्रचार एवं मावनाओं का वे सरलतापूवन शिक्षार नहीं होते। बाह्स की हिन्ट म स्विटलरसण्ड म प्रश्यक्ष प्रजात य की सफलता के लिए उनका स्वदासन म दीपकातीन अनुमव,

सामाजिक समानता एव देशमिक और सावजनिक कतव्य की मावना उत्तरदायी है।
स्विस जनता ने जनमत सग्रह एवं अधिकम का अस्य त बुदिमानी स प्रयोग
किया है। 1848 ई से 1967 ई तक सबीय सविधान के सदीधन के लिए 96
बार जनमत सग्रह हुए हैं जिनम 54 सदीधन जनता क द्वारा स्वीकार किय गर्थ हैं।

स्पप्ट है कि विधायका की अपेक्षा स्थित जनता अधिक अनुवार प्रमाणित हुई है। सामा प्यत जनता ने जटिल एव व्यापक विधिया को अस्वीकार किया है।

प्रत्यक्ष विधान के सम्बाध म स्ट्राग का निष्कष यह है कि राजनीतिक सत्याओं का स्थायित्व एव उनकी उपयोगिता उस समाज की स्थिति पर निभर करती है जिसते उनका सम्बाध होता है। यह महत्वपूण है कि सस्याओं को स्थालित करने वानी जनता की क्षमता से उनको अग्रिम (advance) नही होना चाहिए।¹⁶

¹⁶ Strong, C F op cat, p 231

16

ससदीय विशेषाधिकार [PARLIAMENTARY PRIVILEGES]

ससदीय विशेषाधिकार से तात्यय विधानमण्डलो एव उनके सदस्यो और सिम तियो के विशेषाधिकारों से हैं। सर इस्किन ने ब्रिटिश ससद के सदम में विशेषा धिकार की तिम्नवत व्यारमा की है

"ससदीय विशेषाधिकार उन विचित्र विधितारों का योग है जिनका ससद रूपी उच्च यायालय के अभिन अग के रूप मे दोना सदन मामूहिक रूप से और दोनों सदना के सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से उपमाग करते हैं और जिनक अनाव मे उनके द्वारा अपने कतस्या को सम्पादित नहीं किया जा सकता तथा वो अप निनायों एव व्यक्तियों द्वारा प्राप्त अधिकारों से अधिक होत है। अत विश्वेषाधिकार विधि का अग होते हुए में। एक निध्चित्र सोमा तक सामाय विधि से विभक्त होते हैं।"

कीय के अनुसार ब्रिटिश कॉम स सभा के विशेषाधिकार उन शक्तियो एव अधिकारों का प्रतिनिधित्व करत है जो प्रारम्भ म किसी सभा के द्वारा अपने एव अपने सदस्यों के रक्षाथ आवश्यक माने गये थे। सदन के विशेषाधिकारों एवं कार्यों में स्पष्ट अंतर होता है। विशेषाधिकार का प्रयोग इंस्किन की हृष्टि मं प्रत्येक सदन

2 Keith Constitutional Lau, 7th edn , 1946 p 68

I Parliamentary privileges is the sum of the peculiar rights employed by each house collectively as a constituent part of High Court of Parliament and by members of each house individually without which they could not discharge their functions and which exceed those possessed by other bodies and individuals. Thus privilege, though part of the law of the land, is to a certain extent an exemption from ordinary law —Sir Thomas Erskine May Treatise on the Law Provileges Proceedings and Usagis of Parliament 18th ed., 1971, edited by Sir Barnett Cocks, p 64

के उन मूल अधिकारा की रक्षा हेतु आवश्यन होता है जा गामा यत उसक सवधानिक नायों का सम्यादित नरन हेतु आवश्यन मान जात है। उदाहरणाय, कमी-कनो नों मस की वित्तीय प्रक्तिया नो जो उस नाउन एवं साउसमा ने सदम म प्राप्त है वित्तीय विदेशाधिनार नहां जाता है। विसी वित्तीय शिक्त हुतु विगेपाधिनार वा सवधानिक सिक्त ना प्रयाग सम्य यत प्रक्ति ने स्वच्छा पर निमर करता है। इस्तिन के राज्या म, 'विरोपाधिनार ना प्रयाग मुण उसका अधीनस्य स्वच्छ है। सस्तिय विरोपाधिनार के अधिवार है जा ससद नी प्रक्तिया विपाय प्रमु के लिए आवश्यक हात हैं।' ससद के सदस्यमण उनका उपयोग इसित्य करता हैं नि ससद अपन सम्या की अहीनय सेवा के अभाव म अपन कार्यों को सम्यादित करन म असकत रहता है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक सदन अपन सदस्या एवं उनकी सत्ता एवं सम्मान के रक्षाय उनका उपयोग वरता है। 'अत ससदीय विरोपाधिकार स्वयं अपन म साध्य नहीं है

अपितु ससदीय कार्यों की पूर्ति हेतु एक आयरयक एवं वाहतीय साधन है।

इन विरोपाधिकारा का जब निसी व्यक्ति या अधिकारी द्वारा अतिक्रमण या

उपक्षा की जाती है ता वह विरोपाधिकारा का हनन माना जाता है एवं दण्डनीय
अपराध होता है। प्रत्यक सदन को एस सभी कार्यों के लिए दण्ड दन का अधिकार
होता है जो विरोपाधिकार का हनन न होत हुए भी ससद की विधि के अन्तात तसद
की सत्ता एवं सम्मान के विश्व अपराध होते हैं, जव-सबदीय आदेगा की उपेक्षा
या ससद एवं उसक सदस्या पर दोपारोपण आदि। इंक्किन के अनुसार, "एसे काय यदि
विरोपाधिकार का हनन कहे जात है पर तु वास्तव म वे मानहानि (contempt)
सम्बाधी कार्य होते हैं।"

प्रत्येक विधानमण्डल के लिए इस प्रकार की शक्तियों अपने नायों एव दायित्वं के सम्पादन के लिए आवश्यक होती हैं। उनक अमान म विधानमण्डला म अनुताल कामम रखना कठिन हो जाता है। ससद के कार्यों, विशेषाधिकारा एव अनुशासनासक पित्रयों म घनिष्ठ सम्ब घ होते हैं। अत विशेषाधिकार ससद वे कार्यों एव अनु शासनात्मक शक्तियों के आवश्यक प्ररक के रूप महै।

इस्किन में के जनुसार कुछ अधिकार एव विमुक्तियाँ (immunities) जस बरी न बनाये जाने एव मापण की स्वत तता कुछ ऐसे अधिकार हैं जो प्राथमिक रूप

³ Erskine May Parliamentary Practices op cit, p 64

⁴ उपरोक्त, पृ 64

⁵ उपरोक्त, पृ 65

^{5 &#}x27;Such powers are essential to the authority of every legislature. The functions the privileges and disciplinary powers of a legislative body are thus necessary complement of the function and the disciplinary powers of the privileges "—Erskine May op at p. 64



सम्याप म ससद सदस्या का पूण अधिकार प्राप्त हैं। यम्बीर अपराध ही मम्बद इसका अपवाद हा सकता है।

(2) ससद सदस्या का प्राप्त दुष्ठ, व्यक्तिगत विद्योपायितार । इनम सवाधिक महत्वपूर्ण विद्योपायिकार यह है कि सदन ने सत्रशाल एव सदन के अधिवशन के 40 दिन पूत्र ≣ एव पश्चात तक सदन ने सदस्या भी बादी न बनाय जान का स्वतंत्रकी तथा जह सदन में बाद विवाद भी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है।

(3) सदन की मानहानि सम्बन्धी निजयां का क्रियाचित करन की गिक्त या विज्ञेपाधिकार । एसी अवस्था म सदन अपन सदस्या की या अप किसी भी व्यक्ति को सदन की मानहानि या विज्ञेपाधिकार के हुनन के लिए दिण्डल कर सहता है। इसका प्रमाण मिडिलसक्स के वेरिक का विवाद (Case of the Sheriff of Middleset) प्रमाण की

इंस्कित में के अनुसार विदापाधिकारा के हनन को हम निम्न चार श्रेणिया म विमाजिस कर सकते हैं 9

(1) किमी सदन के सामान्य ससदीय आदद्या या नियमा का उल्लंघन।

(2) विशिष्ट जादेशा या नियमा का उल्लंघन ।

(3) ससदीय काय पद्धति की निदा करना।

(4) ससद सदस्या पर आक्रमण करना या उनको अपमानित करना या उनक चरित पर तथा ससद म उनके आचरण पर अनुचित आक्षेप लगाना या ससद के अधि कारिया के कत∗य सम्पादन म हस्तक्षेप करना ।

कुछ प्रमुख संसदीय विशेषाधिकारा की समीक्षा निम्नवत है

ससदीय विशेषाधिकारों म मापण की स्वतः तता का विशेष महत्व है। धर इंक्लिन में के अनुसार मापण की स्वतं प्रता करवत न परिषद या विधानमध्य का आवस्यक विशेषाधिकार है। 11 दिसम्बर 1667 ई के कॉम ससमा क सम्मत्त म इस सिद्धात की वाक्षित समोक्षा निम्न शब्दा में हुई थी 10

"इतम किसी को कोई स देह नहीं हो सकता कि एक बार जो पारित कर दिया जाता है वह विधि सम्मत होता है सदस्या को यहाँ अपने घरा की माति ही स्वत न होना चाहिए। ससदीय विधि राज्य को नष्ट नहीं कर सकती।" विधि के पारित होने के पूत्र जस पर बाद विवाद अपितत है। फलत बाद विवाद राज्य के सिए परेशामी का कारण नहीं हो सकता।

इसके पूच 1621 ई में ही नॉम स ने आपण की स्वत तता को एक प्रस्ताव द्वारा स्वीकार किया था। इस प्रस्ताव के अनुसार ससद या उसके कार्यों तथा ससद मे

⁹ Erskine May quoted by Maitland in The Constitutional History of England, Cambridge 1941, p 379

¹⁰ Erskine May op cit p 70

मावता, विचार, तक एव वाद विवाद की स्वय सदन द्वारा अमियोग को छोड़कर सदस्यों को अभियोग एवं व दी बनाये जाने से पूण स्वत नता प्राप्त हागी। 1688 ई की क्रान्ति के परचात मापण की स्वत नता विषयक विद्येषाधिकार का साविधिक मा यता प्राप्त हो गयी थी। अधिकारपत्र [Bill of Rights] की नवी धारा म यह स्पट्त घोषित कर दिया गया था कि ससद म नापण की पूण स्वत नना हागे एवं किसी मो यायालय या ससद के बाहर किसी मो स्वान पर ससद म वार-विवाद ना हागे एवं कि लए काई अमियोग नही लगाया जा सनेगा और न ही इम सन्व पत्र न्यू न्यू न्यू के जा सनेगी। में के अनुसार जररीक धारा के अताव प्रत्येक न्यन नता हागे ही बासे के प्रत्यार की काई की अपन सदस्या का उन्हें प्रवस्त के निम्म दण्ड देन का अधिकारी है। 11

पेट जिटन म जाज स्थिति यह है कि संसदीय निवनों के बरूज जनवर संस्था को सदन म अपन विचार स्वतात्रतापुर्वक व्यक्त करन दृह प्रशिद्धार है, पूर्व ही जनस विचार किसी व्यक्ति या व्यक्तिया के लिए हानिप्रद या व्यक्तिक द उत्साम करने वाले हो । प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार सी स्वरन्तर वाहर है ? उन्हरित ससवीय सदस्या द्वारा इस अधिकार के दुश्ययात की न्या की न्या की निर्माण के लिए इस प्रकार की स्वतानता वाधनीय है। या बाँच व ब्लाइट समान (ह्या है। 18 लेकिन इसका यह अथ नहीं है कि विधाननाइन ने नका कर करण वर करा ह अतर्गत ब्रिटिश संसदीय सदस्या को अनगर प्रचार का प्राप्त का प्रमुख विविषय एम्सन के अनुसार मले ही यह रहा राजिय कि साम का जिल्ला का कार्या हा स्वतात्रता है परात इस स्वतात्रता का अप सम्बद्ध के उसके प्रतिकृत सामन का स्वत नता से नही है। "सदन अपन सदस्या है कार्न कर किए तर हरना है एव की निवा करके, सदन वे कार्यों का न्यां हरू करते कर देहर न्य मनदा है, जिला-सित करके उन पर निय त्रण परता है। इन्हें इन्हें इन्हें के अपने का प्रयोग निर्मा नाम का अनुचित एव सम्मानहीन इह है जीन नामुन्द्र मा विद्या नाम न या व्यक्तिगत सदस्य के प्रति आर्थान्त्र हुन्द्र हुन्द्र हुन्द्र हुन् हुन् हुन् हुन् अपराध है जिनके बारे म बावर है हा जा करने

आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने के अपराध में बाफी सदस्या का दण्ड दिय गये है । अनेक सदस्या को प्रताडना, कारावास एवं काम स समा स निष्कासन का दण्ड दिया गया है। सर इस्किन का कथन है कि काम स समा के अनुशासन सम्बंधी विशेपाधिकारो को सदन व अध्यक्ष क जादेशा स सम्पृष्ट किया गया है।16

मापण की स्वतायता के विशेषाधिकार की रक्षाथ (1) प्रत्येक सदस्य का यह कत य है कि वह कोई कार्य उस विदोपाधिकार के निपरीत न करे जिसका वह उपमोग करता है । उसे किसी बाह्य व्यक्ति या सस्था या निकाय के साय ऐस कोई अनुवाध नहीं करने चाहिए जिनसे संसद सदस्या की पूण या आक्षिक स्वतन्त्रता नियनित होती हो । उसका ऐसा हर अनुवाध या काम ससदीय काम एव दायित्व के विपरीत माना जाता है। (2) काम स समा की बठके मुप्त होनी चाहिए और उसम बाहर क किसी सदस्य की उपस्थित नहीं होना चाहिए। यदि कोई वाह्य व्यक्ति कामन्स समा के अधिवेशन म उपस्थित रहता है तो उस य दी बनाया जा सकता है । (3) अपनी कामवाही के प्रकाशन पर कॉम स समा को प्रतिबाध लगाने का अधिकार है । गलत एव असत्य वाद विवाद का प्रकाशन विशेषाधिकार का हनने माना जाता है एवं सदन को ऐसे अपराध के लिए दण्ड देने का अधिकार है। (4) ससद के दोनो सदना के आदेश से प्रकाशित पता के सम्बाध मा यायालया के हस्तक्षेप स विधिक सरक्षण प्रदान निया गया है। यदि कोई सदस्य अपना कोई ऐसा मापण प्रकाशित करता है जो सस दीय बाद विवाद का अश नही है तो वह भाषण की स्वत नता के विदोपाधिकार क अन्तगत रक्षा प्राप्त करने का अधिकारी नही है और वह सामाय विधि के अन्तगत किसी भी आपत्तिजनक भाषा के प्रयोग के लिए यायालय के समक्ष उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। (5) भाषणकी स्वतात्रता का विनेपाधिकार उन सभी गवाहा, आवेदको व अभिमावको को भी उनकी कथनी एवं करनी के लिए प्राप्त होता है जो वे सदन या समिति में कहते व करते है एव इन विचारों के लिए उन्हें यायालयों में उत्तरदायी नहीं ठहरावा जा सकता। (6) किसी भी सदस्य को सदन म व्यक्त विचारा के लिए चाहे वे कितने ही जपराधी प्रकृति के क्यो न हो, सामान्य अदालत मे उत्तरदायी नही टहराया जा सकता। किसी सदस्य द्वारा यदि सदन मे कोई फीजदारी अपराध किया जाता है ती सदनको उस सम्य ध मे कायवाही करने का पूण अधिकार होता है । लेकिन इस सम्बध में कोई सवसम्मत मत नहीं है। सर इस्किन में के अनुसार काम स समा के फीज-दारी कार्यों की क्षेत्राधिकार सम्ब घी विधिक स्थिति स्पष्ट नही है। 16 इसके विपरीत, 'पायाधीश स्टीफेन ना यह सुस्पष्ट मत था कि कॉम स समा मे किये गये किसी भी साधारण अपराध के लिए सामा य यायालयों म मुकदमा नहीं चल सकता है। म सर

¹⁴ Erskine May op cit, p 72 15 Erskine May op cit p 87 16 Bradlaugh v Gossett, 1884 12 Q B D 271, cited by Erskine op at p 87

विलियम एन्सन¹⁷ भी जस्टिम स्टीफेन कं मत को स्वीकार करत है। परातु सेटलंण्ड का कथन है कि यदि कॉमन्स या लाड समा का कोई सदस्य चोरी करता है तो उस सामा य रीति से सामा या यायालया द्वारा ही दण्टित किया जाना चाहिए। 18

ब्रिटिश ससद के अय विश्वेपाधिकार निम्नवत हैं

- (1) ससदीय विशेषाधिकारा के हुनन एव मानहानि सन्य थी कार्यों दी सूची पर्याप्त लन्यी है 1° सामा मत किसी सदन के सम्यादन में याथा डालना किसी सदस्य या सदन के अधिकारा एव नत्तव्य-सम्यादन म प्रत्यक्ष या अवत्यक्ष रूप से वाधा जलपम करना या वे सची कार्य जिनके उपराक्त परिणाम हो सकने हैं मानहानि (Contempt) समक्ते जाते हैं। सदन या उसने दिसी समिति में अपमानज क आचरण को मानहानि माना जाता है।
- (iii) कॉम स समा का दण्ड सम्बन्धी क्षेत्राधिकार (Penal Jurisdiction of House of Commons)²¹ के अधीन ससद क दांना सदना को अपने सदस्या को या अप आसियों को सदन या उसके बाहर अशिष्ट आवरणों या अपराधा के लिए दिण्डत करने की सदन में ने मानहांनि के लिए दिल्त करने की सदन में मानहांनि के लिए दिल्त करने की सदन में हैं। इस दिल्ल का सामग्री प्रकार सदान की हैं। जिट्टा नामाधीशा न ससद की मानहांनि के लिए स्वरान रूप में दण्ड दन के अधिनार को स्वीकार किया है। उदाहरणाय, मिडिलसेसर के रीरिफ (Sheriff of Middlesex)

¹⁷ Anson op al , p 186

¹⁸ Maitland op cit, p 321

¹⁹ Erskine May op cat, Ch VII, pp 89 103

²⁰ Ibid , p 104

²¹ Erskine May op cit, Ch IX, p 112

²² Erskine May op cit, p 113

ने मामले म मुख्य यायाभीय न निषय दत हुए कहा था कि 'त्रतिनिधि निराम। का क्वा अपने साधना स अपनी सत्ता का बचाव न रना चाहिए। 12 मुख्य यायाधाउ एलानवरों की हिष्टि म काम स की मानहानि एव विद्यापिकारों क हुनन के लिए दुग्र दिन की धामता के चुनीती नहीं दी जा सकती स्वरक्षा एव बचाव नां यिक काम से हायों म होनी चाहिए। 1 छाट एव हुनके अपराध के लिए अपराधी की त्रताड़ना एव कस्ताना की जाती है। सदस्या ना मानहानि के अपराध म सदन स निष्मा सत्त स अवस्था के लिए निषम्यन का स्वर्ण का स्वर्ण के लिए निषम्यन का स्वर्ण स्वर्य स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स

समदीय विश्वपाधिकार के शंत्राधिकार रे प्रदेन को लेकर ब्रिटिश 'यापानवा एवं ससद स समय समय पर मचय होत रह हैं। लेकिन विगत 100 वर्षों से ब्रिटिश 'याबा जय एवं ब्रिटिश' ससद म इस सम्बाध म एक गामबताऊ सममदारी का विकास हुआ है। फिर भी अतिम रूप संयह नहीं कहा जा सकता कि इस समस्या का समाधान हीं चुका है। आज स्थिति यह है कि ब्रिटिश 'यायालय ससदीय मानहानि के सम्बर्ध म काम'म समा के निणय वो पुणकरण स्वीकार करते हैं।

सदन क विदायाधिकार वे हनन या मानहानि के आरोपा क सम्बन्ध म कार्यन्त समा या लाडनमा के अव्यक्ष द्वारा प्रारम्भिक जांच की जाती है। यदि इस जांच के लाधार पर यह निविचत निया जाता है कि विद्योदाधिकार का हुनन मा अतिनमण हुन्ग है या सदन की मानहानि हुइ है तो सामला सदन या विद्याधिकार समिति के समक्ष निवार हुतु अन्तुत कर दिया जाता है। अपराधी को अपने बचाव का समुधित अवसर प्रदान निया जाता है।

लाडसभा के विधोपाधिकार निन्न हैं दीवानी मामलो मं व दी न बनाय वाने की स्वत तता वाद-विवाद की स्वत तता, सझाट स व्यक्तिगत रूप से मिलने की स्वत तता एव मानहानि के लिए दण्ड देने का अधिकार। जिस प्रकार काम स के स्वतः तता एव मानहानि के लिए दण्ड देने का अधिकार। जिस प्रकार काम स के स्वीकर द्वारा विराधानिकार की विधिवत मांग की जाती है उसी प्रकार लाडसभा द्वारा उनकी विधिवत मांग नहीं की जाती है, अपितु वे स्वत त रूप स लांडसभा को प्राप्त हैं।

स्टरम के अनुसार लाडसमा के व्यक्तिगत सदस्यों के विश्वेपाधिकार कॉम स सम के व्यक्तिगत सदस्यों के विश्वेपाधिकारों से पूषक होते हैं, दोनों को ही ससदीय सदस्य के रूप म समान विश्वेपाधिकार प्राप्त है, लेकिन लाडसमा करस्यों को पीयरा के रूप में काम स समा ने सदस्या स सवया पूषक विशिष्ट विश्वेपाधिकार प्राप्त होते हैं। पै पीयर के रूप म उपलब्ध विश्वेपाधिकार ससदीय विश्वेषाधिकार सी मिन्न है। पीयर

²³ The Case of the Sheriff of Middlesex, 1840, see Kerr and Lawson op cit, p 142

²⁴ Burdett vs Abbot, 1811

²⁵ Stubbs quoted by Erskine op cit, p 64

के विशेषाधिकार सभी पीयरो को उपलब्ध होते हैं, मले ही वे लाडसमा के सदस्य न हो। इसकी सीमा एवं क्षेत्र स्पष्ट नहीं हैं। [©]

दोना सदनो को विद्योपाधिकारों के प्रधासन म समान अधिकार प्राप्त है। दोना सदनो द्वारा पृथक रूप स स्वत जतापूवक इनका उपमोग किया जाता है। कुछ विद्योपाधिकार ब्रिटिश ससद की विधियो एव परम्परावो (Customs) पर आधारित हैं। कुछ परम्पराक्ष दिटश ससद की विधियो एव परम्परावो है। 17 कोई एक सदन नदीन विद्योपाधिकार वा मुजन नहीं कर सक्ता। 8 1966 ई म कॉम स सम म सस-दीय विद्योपाधिकार वा मुजन नहीं कर सक्ता। 8 1966 ई म कॉम स सम म सस-दीय विद्योपाधिकार की समीक्षा के लिए एक प्रवर समिति की स्थापना की गयी थी। सामित न 1967 ई म प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन म विद्योपाधिकारों के क्षेत्र एव मान-हानि विषयक कुछ नवीन सिफारिश वी थी सेकिन इन पर तत्वाल कोई निणय नहीं लिया जा सका। 18

भारत में संसदीय विशेषाधिकार

मारतीय सिषधान के अनुच्छेद 105 एवं 194 के अं तमल ससदीय विशेषा विकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 105 का सम्ब व ससद, उसके सदस्यों एवं सिनितया से हैं तथा अनुच्छेद 194 राज्य विश्वानमण्डल, उसके सदस्यों एवं सिनितया से हैं तथा अनुच्छेद 194 राज्य विश्वानमण्डल, उसके सदस्यों एवं सिनितया में विदेषाधिकारों से सम्बिधन है। मारतीय सबस सदस्यों ओ सिषधान के उपनेपाण की स्वत तता प्राप्त है। ससद या उसकी सिनित में व्यक्त विचारों एवं मतिया में विद्यान के विवार मायण की स्वत तता प्राप्त है। ससद या उसकी सिनित में व्यक्त विचारों एवं मतवान के लिए या ससद के किसी सवन के अधिकाराजुमार प्रस्तुत किसी आपन पत्र, मत या कायबाही के प्रकाशक हिल्प किसी सदस्य को किसी यायावय में उत्तरदायी नहीं टहराया जा सकता। 100 विद्योगधिकार निधारित करने का अधिकार मारतीय मसद को सिन्धान के द्वारा प्रदत्त है। जब तक भारतीय ससद इस सम्ब ध में किसी विधि का निर्माण नहीं करती उस समय तक भारतीय ससद के भी चही विद्यापिकार होग जिनका उपनोग प्रिटिश ससद की कॉम स सभा एवं उसके सदस्य तथा समितयों द्वारा किया जाता है। अपना के अनुतार उपरोक्त समी अधिकार उन सभी व्यवस्य को मी ससदीय सदस्या को भाति ही प्राप्त होने जिल्ही कि सिव्यान के अपीन मदन में भाषण का

²⁶ Erskine May op cit, p 68

²⁷ Ibid, p 66 28 Ibid p 69

²⁹ Ibid , p 69

³⁰ अनुच्छेद 105 (1) व (2)

³¹ अनुच्छेद 105 (3)

अधिकार प्राप्त होगा या जो सदन या किसी समिति की कायवाही म माग सर्ग । अर्जु च्छेद 194 के अत्तगत उपरोक्त सभी व्यवस्थाएँ राज्य विधानमण्डल को भी प्रदान प्री गयी हैं । मारत में विद्योपाधिकारा को विधिवत् सहितावद्ध नहीं किया गया है, फतत विभिन्न अवसरो पर अनेक विवाद खडे होते रहे ईं ।

मारत म विधानमण्डल के सदस्या की भाषण की स्वतन्त्रता पर सविधान क विभिन्न उपय धी एवं सदन की कायपद्धति सम्ब धी नियमा के प्रतियन्ध हैं। उदाहरण के लिए, सामाजिक महत्व सम्ब धी प्रस्ताव को लोकसमा म उपस्थित करने के लिए कायपद्धति के निम्न नियमों की पूर्ति आवश्यक है ³

ति के निम्न नियमों की पूर्ति आवश्यक है ^३ (1) प्रस्तान की मापा स्पप्ट एन सुगठित होनी चाहिए ।

(2) प्रस्ताव को एक ही प्रश्न से सम्बन्धित होना चाहिए।

(3) प्रस्ताव म तकों, निष्कर्षों, व्यगातमक सम्बोधनो, आरोपा एव नि दाजनक

वाक्या का प्रयोग नहीं होना चाहिए । (4) प्रस्ताव मे व्यक्तियों के पद एवं सावजनिक आचरण सम्बंधी तथा वरित्र

के अतिरिक्त अय किसी आचरण एव चरित का उल्लेख नहीं होना चाहिए । (5) प्रस्ताव में ऐसे किसी मामले का उल्लेख नहीं होना चाहिए जो याग

() प्रस्ताव भ एक्ष किसा मामल का उल्लेख नहीं होना चाहिए ची विश्वास्त्र स्था में विचाराधीन हो।
स्पीकर द्वारा स्थीकृत होन पर प्रस्ताव पर लोकसभा में विचार-विमय ही

स्थाकर द्वारा स्वाकृत होन पर प्रस्ताव पर लोकसमा म विचार-विमय छ। सकता है परतु स्थीकर को किसी प्रस्ताव को विचार हेतु स्वीकृत करने के पूव उप रोक्त वातो के अतिरिक्त निम्न बातो का भी ध्यान रखना चाहिए 33

प्रस्ताव का सम्ब ध निकट भूत म घटित किसी घटना से ही होना चाहिए।
 यदि किसी मामले पर किसी सन म पहले बिचार हो चुका हा तो उसपर

(2) यदि किसी मामले पर किसी सब सपहले विचार हो चुका हातो उस^{पर} पुन विचार नहीं हो सकता।

(3) ऐसे मामलो पर भी विचार नहीं किया जाता चाहिए जिन पर भविष्य म विचार होने वाला हो।

हमके अतिरिक्त लोकसमा की कायपद्धित सम्ब धी कुछ सामा य नियम मी होते है। इन नियमा क अनुसार किसी सदस्य को मायण देते समय ऐसे किसी भागते की उल्लेख नहीं करना चाहिए जो यायालय के विचाराधीन हो, न अप किसी सदस्य पर अस्तिमत आसेप करना चाहिए और न ही ससद की कायवाही के विदद्ध आपत्तिजनक माया का प्रयोग करना चाहिए। राष्ट्रपति के नाम ना भी उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सदस्यों को अपने मायणों में राजदोहासक एव युड्य प्रकारी तथा

³² Refer Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, Ch XIII, 5th edn. 1957

³³ Ibid, Ch XIV

नि दात्मक राज्या वा प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाषण वे अधिकार का प्रयोग किसी भी सदस्य द्वारा सदन की वायवादी का स्थमित करन वे विए नहीं करना चाहिए। 1³¹ लोवसमा के अध्यक्ष का आपश्चित्यक आपरण के लिए सदस्यवाणा को अप दिन के लिए निष्नासित करन का अधिवार प्राप्त है। 1³⁵ अध्यक्ष में आपा का उल्लयन करा बात सदस्य को यह नामाकित कर सकता है, जिसका अर्थ यह है उस सदस्य का उस सप्त के प्रदेशन में निए निष्कासित किया जाता है। 1⁴⁸

बिटिस ससद नौ मापण की स्वतन्त्रता की धारणा मारत म सी पूरी तरह मा य है। सचलाइट (पटना) के मुकदमे म सर्वोच्च प्यावालय ने यही सब श्रिवपादित विचा है। इस मुकदमे म यह तक प्रस्तुत किया गया चा कि अलोकता त्रीय काल म मा य द्विटिंग मादीप विदोपाधिकारो वा मारतीय समद या राज्य विचानमण्डला क सदम म लागू नहीं क्या जाना चाहिए क्यांचि यहाँ की धर्मिस्यतियाँ जिटेन स सित्र है। न्यावालय ने इस तथ को अस्वीकार करत हुए कहा था कि हमारे सविधान ने स्पष्ट रूप म ससद या राज्य विधानमण्डलो से सम्बर्धित शक्तिया, विद्येपाधिकारो एव उम्मुक्तिया की व्याव्या की है। सविधान के फ्रियाव्यम के पश्चात उन्हें ने सद शक्तिया जियोधिकारो एव उम्मुक्तिया होते हो स्वाव्यान स्वाव्या के अपन्त है। कॉम समा जय इनका उप मोग करती हो तो उस समय इन्हें मारतीय सच्च को प्रदान न करने का अय सविधान का पुनिनिर्मोण होगा, न कि उत्ववी क्यांच्या करना।

अय विश्वेषाधिकार जैसे व वो न बनाय जाने की स्वत-नवा एव मानहानि तथा विश्वेषाधिकारों के हनन पर दण्ड देने का अधिकार भी भारतीय ससद एवं विधान-मण्डला को बिटिश ससद की मांति पूणक्ष्मण प्राप्त है । विटिश कॉम स समा की मण्डला को बिटिश सासद की मांति पूणक्ष्मण प्राप्त है । विटिश कॉम स समा की मांति मारतीय सामक्षमा ने भी विश्वेषाधिकारों के हनन तथा सदन की मानहानि के लिए, सितस्वर 1951 ई म थी मुद्दश्त को विश्वेषाधिकार समिति हारा दोधी ठहराय बान पर सदन से निष्कासित कर दिया गया था । ससद सदस्य थी देशपाष्टे को निवान्क निरोध अधिनियम के अश्रेत 1952 ई म ब दो बनाया गया था । विरोध विकार समिति ना यह मत या कि निवारक निरोध अधिनियम के अश्रेत नजरव वी स सदस्य क विरोधाधिकार का हनना हो होता है । एक अय मामनर टाइम आफ इरिश्या पत्र से सम्बर्धित है । इस पत्र न एक समादकीय प्रकाशित किया था । विरोध विकार समिति ने इस सम्पादकीय के कि लिए समावार पत्र एय सम्पादक पी सदस्य

³⁴ Ibid, Ch XXVII

³⁵ Ibid , Rule 373 36 Ibid , Rule 374

³⁷ Pandit M S M Sharma vs Shri Krishna Sinha and others B C J, Vol XVII, p 940



कि ब्रिटिय कॉम स समा की तुलना मे अधिकाश राष्ट्रमण्डलीय देशों म विधायका की

संगुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस द्वारा मानहानि के लिए दण्ड देने की शक्ति **आलोचना विषयक अपेक्षाकृत** अधिक स्वतः नता प्राप्त है । का समय-समय पर प्रयोग किया गया है। प्रतिनिधि सदन इस इक्ति का उपमीग जाव समितिया विरोध कर अमेरिका विरोधी कार्यों से सम्बीधत खिमिति—The Committee on un American Activities—के माध्यम से करता है। शेकिन मानहानि के तिए काग्रेस द्वारा दण्ड तीव्र विवाद का विषय वन गया है। मानहानि के लिए दण्ड देने का अधिकार सिवधान द्वारा काग्नेस को प्रदत्त नहीं है फिर मी इसे विधानमण्डल की अपने दायित्व सम्पादन के लिए आवश्यक माना गया है। पर तु अमेरिकी विधान-मण्डली द्वारा इसका बहुत कम प्रयोग किया गया है। सीनेट के सदस्यों को सदन मे अनियाणित भाषण की स्वत जता प्राप्त है। ब्रिटिश कीम स सभा एवं अयं राष्ट्रमण्ड-सीय देशा की तुलना म अमेरिकी कांग्रेस के सदस्या को अपक्षाकृत मापण की स्वत त्रता अधिक है। 10

17

कार्यपालिका [EXECUTIVE]

अयं एव प्रकृति

कायपालिका शासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जग माना जाता है एव सामाय जनता कायपालिका को ही शासन समक्रती है। व्यवस्थापिका के द्वारा निर्मित विधिपो के आधार पर कायपालिका देश के शासन का सचालन करती है। दूसर शारा म, कायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित विधिया को क्रियावित करती है । कायपालिका से अप सामा यत शासन के उन अधिकारिया या उन निकायो स है जिनका दायित दर्श की विधिया का किया वयन या पालन करना होता है। व्यापक अध में, गेटेल के जुर् सार, कायपालिका मे शासन के वे सब कमचारी सम्मिलित होते है जो व्यवस्थापिक और पायपालिका के सदस्य नहीं होते एवं वे सभी विभिक्षण भी सम्मिनित होते हैं जा विधिया के रूप म अभिव्यक्त राज्य की इच्छा को कियावित करत हैं। मिनी अप म कामपालिका का अथ केवल उसके अध्यक्ष स होता है, उदाहरणाय, संकृत राज्य अमरिका या मारत का राष्ट्रपति । व्यापक अथ मे कायपालिका के अतम्त कायपालिका का अध्यक्ष, कायपालिका समिति, मिनमण्डल, नौकरशाही एव सनिक सेवाएँ भी शामिल होती है। फाइनर के अनुसार, "शासन के अय अगा-व्यवस्था पिका एवं "यायपालिका द्वारा अपने भाग की शक्ति को लेने के पश्चात जो गर्कि गर्प बचती है वह कायपालिका शक्ति कहलाती है। अत कायपालिका शासन की प्रविपद शक्ति है। 2

¹ Gettell Political Science, 1956, p 331

^{2 &}quot;The Executive in the residuary legatee in Government after other claimants like Parliaments and the Law Courts have taken their share —Finer The Theory and Practice of Modern Government, 1956 p 575

विलोधी सहय कुछ विद्वान धासन की कायपालिका एव प्रशासकीय (Admi nistrative) द्वालाओं में भेद करते हैं 13 कायपालिका को वे राजनीतिक अंग मानते हैं जिसका मुख्यत नीतिया एव नवीन योजनाओं के निर्माण सं सन्दाय होता है। इसे व्यायक निर्मायक द्वाला प्रवाद हांती है। राज्य म विषयों को निर्मायित करना तथा अन्तर्राय एव सैनिक सन्धियों को व्यवस्थित करना कायपालिका का दायित्व एव क्तव्य हाता है। प्रशासन (Administration) द्वासन का अराजनीतिक मांग है। इसका काय वायपालिका के निर्माय द्वासन की नीतिया को क्रियाचित करना होता है। वे नीति निर्माण मंभी भाग सेत हैं विकिन वे उसके लिए उत्तरदामी नहीं हाते। प्रशासनिक अधिकारियों का मुख्य काय विनम्नतिदिन के प्रदासन का सवालन करना होता है।

कायपालिका, व्यवस्थापिका तथा वायपालिका के भेद उनक कायों की प्रकृति पर आभारित होत हैं। कायपालिका की सफसता हेतु बीधा निणय बुद्धि एव काय- समता तथा कमठता की आवश्यकता होती है। एक सीमा तक कायपालिका के कार्यों में गोपनीयता भी अनिवाध है। इस हुन्टि से कायपालिका वालि एक या थीडे सं व्यक्तियों के सुष्या में हानि चाहिए। विचार-विषय की हुन्टि से व्यवस्थापिका में अपिक सख्या एक वाध्यीय तत्व है लेकिन बीध काय करने की हुन्टि से यह सबसे बड़ा दुर्गुण भी है। अत राजनीतिक अनुमव से एकल अध्यक्षीय कायपालिका का पक्षप्रीयण होता है।

कायपालिका के प्रकार

कायपालिका को निम्न वर्गों म विभाजिन किया जाता ह

(1) एकल एव बहुल बायपालिका (Single and Plural Executive),

(2) वद्यानुगत एव निवाचित कायपालिका (Hereditary and Elected Executive),

(3) নামমাস एব বাংলবিক কামণালিকা (Nominal and Real Exe cutive),

(4) सस्दीय एव अगसदीय कायपालिका (Parliamentary and Non Parliamentary Executive)।

चपर्युक्त वर्गीकरण चार सिद्धान्तो पर आधारित है । प्रथम वर्गीकरण सहया पर आधारित हैं । द्वितीम वर्गीकरण का आधार बायपालिका की नियुक्ति प्रणाली से सम्बन्धित हैं । ततीय वर्गीकरण शासन की शक्ति धारण करने के तथ्य सं सम्बन्धित

³ Willoughby Government of Modern States, Chaps XIV and XVI, cited by Gettell Political Science, 1956, p 332

476 | आधुनिक शासनत त्र

है। चतुर्य वर्गीकरण कायपालिका एव व्यवस्थापिका के पारस्परिक सम्बद्या पर आधारित है।

एकल एव बहुल कायपालिका

एकल प्रणाली म नायपालिना की धांक एक व्यक्ति म अधिरिटत होती है। प्राचीन काल म द्वासन की सभी शक्तियाँ राजा के हाथ म हुआ करती थी। अधुनिक समय मे संयुक्त राज्य अभिरेका की कायपालिका एकल कायपालिका का श्रेट्ट उदाहरण मानी जाती है। अमिरिकी राष्ट्रपति म कायपालिका शक्ति निहित है। अमिरिकी मिन मण्डल राष्ट्रपति के आपन हाता है। मिन्नया का राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया तही है। असि च उसी के प्रसाद पयन्त पदाक्ड रहते हैं। व राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तर दायों होते हैं।

बहुल कायपालिका म द्वासन की बक्ति एक से अधिक ब्यक्तिया या एक समिति म अधिष्ठित होती है। प्राचीन काल म भी बहुल कायपालिका प्रणाली पायी जाती थी। उदाहरण के किए स्पार्टो म दा राजाजा का द्वासन था। प्राचीन एपे स मे काय पालिका शक्ति अनेक अधिकारियो म जिंद जनरस एव जानकून (archons) कहा जाता या, विसाजिन थी। रोम के गणराज्य म दो काउ सल (consuls) होत थ। म प्रव राज्य-नार्ति के परचात 1795 ई म कास मे पाच सदस्या की अपरचरटी के हाणो में कायपालिका शक्ति निहित थी। वतमान समय म स्विद्युज्यकेण्ड में 7 सदस्यी बहुक वायपालिका का विधान है। विशेष के अनुसार स्था म कायपालिका सम्ब थी कुछ याकि मिना की परिवद म निहित है। में मिनमण्डलीय वासन व्यवस्था को मी बहुल कायपालिका म रस्थ छक्ते हैं एरतु यह उचित वर्गीकरण नहीं माना जायेगा वर्गाव सकता के बेबल स्विट्य स्थान प्रमुख होता है। अत उसे बहुल कायपालिका नदी मान सकता के बेबल स्विट्य स्थान प्रमुख होता है। अत उसे बहुल कायपालिका नदी मान सकता के बहुल कायपालिका प्रमुख होता है। स्थानीय वासनो में बहुल कायपालिका प्रमुख होता है। स्थानीय होता है। स्थानीय वासनो में बहुल कायपालिका प्रमुख होता है। स्थान होता कि अध्यक्तिक प्रमुख हिंगा है। निमान कासनो में बहुल कायपालिका प्रमुख होता है। स्थानीय होता है। स्थानीय होता है।

एकल कायपालिका अधिक हदता, एकना एव तलपरना स काय करती है।
नाम गुटव दो का इसम अभाग होता है और मकटकाल म यह अधिक उपयोगी
मिद्ध होती है। बहुल कायपालिका के पक्ष म यह तक दिया जाता है कि एक की अधेशी
कुद्ध व्यक्तिमों में अधिक बुद्धि होती है और एक कायपालिका को अधेशा बहुल काय
पालिका के मीति निर्माण म निषय एवं निकच्य अपेशा बहुत केंद्र पालिका का अधीन निरमुख प निष्य एवं निकच्य अपेशा क्षेत्र होने हैं। बहुल काय
पालिका का अधीन निरमुख एवं अल्याचारी ज्ञामन की सम्मावना वा अमाय रहता है

⁴ Garner Political Science and Government, 1956, p 620

⁵ Gettell op cit, p 333

एव नागरिन स्वत त्रता को अधिक प्रतिभूति होती है। लेकिन अनुमव न यह सिद्ध किया है कि यहुल नायपालिका सामा यत अस तोषजनक होती है। इस प्रणाली के अभीन सदस्या म उत्तरदायित्व विमाजित होता है, फलस्वरूप उनम एकता का अमाव रहता है और सत्ता कमजोर पड जाती है। आधुनिक राजनीतिक विचारको ना सब सम्मत मत यह है कि कायपालिका का सगठन एकता पर आधारित होना चाहिए 16 अमेरिनी विचारक एलेक्जेण्डर हीमस्टन (Alexander Hammiton) ने एकल काय पालिका के पश का समयन करत हुए कहा था कि 'सुशासन की परिमाया का प्रमुख तत्त सदास कथापालिका है। 'वाह्य आत्रमणा एव अराजकता से समाज की रशा स्थायी शासन, सम्पत्ति, स्वतंत्रता एव सामाय याध नी रक्षा के लिए सशक्त काय पालिका कम आवस्यक नहीं होती।' यायाघीश स्टोरी ने भी कायपालिका की एकल प्रणानिका कम आवस्यक नहीं होती।' यायाघीश स्टोरी ने भी कायपालिका की एकल प्रणानी ना समयन किया है।

वशानुगत एव निर्धाचित कायपालिका

यसानुगत नायपालिकाओं में अनिवायत राजा या संभाट कायपालिका के ममुत होते हैं एवं व जाम ने आधार पर राजपद के अधिकारी होते हैं तथा जीनन प्यान प्रदाल्ख रहते हैं। मृत्यु के पदवात उसका उत्तराधिकारी राजा या मुख्य काय पालिका निमुक्त किया जाता है। जत जिस कायपालिका की नियुक्ति क्या परम्परा या जाम के आधार पर की जाती है उसे बद्यानुगत कायपालिका नी सजा देते हैं। काय-पालिका की नियुक्ति ना जाय तरीका निर्वाचन है। निर्वाचित कायपालिका का कायकाल निविचत होता है। निर्दिचत समय के लिए अनता द्वारा उन्हें चुना जाता है। आधुनिक कास अधिकाश देशा म निर्वाचित कायपालिका का वार्ष उन्हें चुना जाता है। आधुनिक कास अधिकाश देशा म निर्वाचित कायपालिका वार्ष जाती है।

प्रेट-ब्रिटेन, नेपाल, प्रिल्यम, नार्वे एव स्वीडन वशानुगत कामपालिका के उवाहरण हैं। बतमान ममय के वशानुगत राजा सामा यत सबैधानिक शासक होते हैं। प्राय सभी देशा म लोकत त्रीय शक्तिया सिनय हैं पर तु कुछ अविकसित दशों में लोकत त्रीय शिक्त करा हो। हा सका है। ऐसे देशों में लोकत त्र अभी भी पूरी तरह अपन परा पर खडा नहीं हा सका है। ऐसे देशों में निरहुद वसानुगत राजत त्रीय व्यवस्था पायी जाती है।

मारत, फास, स्विटजरलेण्ड, समुक्त राज्य अमेरिका आदि देश निर्वाचित कायपालिका के उदाहरण हैं। वायपालिका के निवाचन का कोई एक तरीका नही है। निर्वाचन की अनंक पद्धतिया प्रचलित है। कुछ देशों में प्रत्यक्ष रीति से तो दूसरे देशों में अप्रत्यक्ष रीति से वायपालिका निर्वाचित होती है। माग्त, संयुक्त राज्य अमे-रिना फास, स्विटजरलण्ड में अप्रत्यक्ष रीति से, तो पीरू, ब्राजील, बोलाविया आदि

Gettell op est p 333

⁷ Garner op at, p 619

लेटिन अमेरिकी देशों में प्रत्यक्ष रीति से राष्ट्रपतियां को चुना जाता है। जमनी व वीमर सविधान के अतगत राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित करने की व्यवस्य थी। अमेरिको राष्ट्रपति निर्वाचक मण्डल द्वारा चुना जाता है जिसमे प्रत्येक राज्य व उतने ही सदस्य होते है जितने कि उस राज्य का काग्रेस मे प्रतिनिधित्व करते हैं। फासीसी ससद के दोनो सदन अपने सयुक्त अधिवेशन म फ्रेच राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। स्विस कायपालिका की वहाँ की सघीय व्यवस्थापिका (फेडरल असेम्बली) द्वारा चुना जाता है। मारतीय गणराज्य का राष्ट्रपति ससद के दोना सदना एव राज्य

की व्यवस्थापिकाओं के निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचक मण्डल द्वारा चुना जाता है। अत कायपालिका-प्रमुख का निर्वाचन तीन पद्धतियो से होता है—(1) जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचन, (2) निर्वाचक-मण्डल द्वारा निर्वाचन, एव (3) व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन । निर्वाचित कायपालिका के अध्यक्षों की शक्ति म व्यापक अतर होत हैं। लेटिन अमेरिकी राज्यों क राष्ट्रपतिया की स्थिति किसी अधि नायक से किसी भी प्रकार कम नहीं होती। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति पर्याप्त शक्तिशाली होता है। ततीय एव चतुर्य फेंच गणराज्या के राष्ट्रपतियों की शक्तियाँ नगण्य थी। स्विटजरलण्ड मे राष्ट्रपति केवल कार्यपालिका आयोग का अध्यक्ष मात्र हाता है।

राजनीतिक हिन्द से अविकसित देशा के लिए वशानुगत कार्यपालिका अपेक्षा कृत कुछ विशेष परिस्थितिया मे उपयुक्त हो सकती है। वशानुगत कायपालिका क कारण अतर्राष्ट्रीय मामलो मे प्रतिष्ठा म कुछ वृद्धि होती है । इसके अतिरिक्त शासन में स्थायित्व, उत्तरदायित्व एव जनता म कायपालिका के प्रति सम्मान की मावना इसके अय गुण है। वशानुगत कायपालिका प्रधान देशों में नौकरशाही स्थायी एव सक्षम होती है। वेजहोट के अनुसार 'वदानुगत राजतान एक इड सरकार है क्यांकि यह हरव्य है। राजा शासन एव जनता के मध्य एक कडी का काय करता है और शासन के प्रति जनता की भक्ति एवं आज्ञानुवर्तिता प्राप्त करन म सहज रूप से अपने व्यक्तित्व से योग प्रदान करता है। विटिश राजा एकता ना सूत्र है, समाज का प्रमुख है एवं नितक व्यवस्था का सरक्षक है। 10 लेकिन बद्यानुगत कायपालिका का सबस बडा दोप यह है कि जम के आधार पर नियुक्त कायपालिका योग्यता की कोई गारण्टी नहीं है। 11 गानर के अनुसार इतिहास वद्यानुगत कायपालिका के पक्ष म नहीं है। यह पद्धति भतकालीन अवशेष मात्र है।

⁸ आस्ट्रिया, पोलैंग्ड एव चकोस्लोवाविया म भी वायपालिका प्रमुख व्यवस्थापिका

हारा ही चून जाते हैं। 9 Gettell op at p 335 10 Bagchot *The English Constitution*, Ch 2, 1963, pp 82 98 11 Gettell Ibid p 335

¹² Garner op cit, p 626

नाममात्र एव वास्तविक कायपालिका

कायपालिका द्वारा प्रयुक्त शक्ति के आधार पर उसे नाममान एव वास्तविक कायपालिका मे वर्गीकृत किया गया है। कायपालिका के निर्वाचित होने पर यह आव स्थक नहीं है कि वही वास्तविक कायपालिका हो विक्त यह भी सम्भव है कि वह नाममान की कायपालिका हो, जैसे कि तृतीय एव चतुत्र फेच गणराज्य के राष्ट्रपति तथा मारत के वतमान राष्ट्रपति नाममाज की कायपालिका है। लेकिन सभी लोकता निक वहा मे वशानुगत राज्य को नाममान की शक्तिया प्राप्त होती हैं। लेकिन जिन देशा मे वशानुगत राज्य को नाममान की शक्तिया प्राप्त होती हैं। लेकिन एव वशानुगत राज्य न परस्पर विरोधी हैं। लेकिन जिन देशा म लोकतन के साय-साय राजतान भी होता है वहा वह ऐतिहासिक विकास का परिणाम होता है। इगलब्द मे लोकतान के विकास मे राजतान ने महत्वपूण भूमिका जवा की है। बिटिय राजतान ने लोकतान के विकास मे याजान ने महत्वपूण भूमिका जवा की है। बिटिय राजतान ने लोकतान के विकास मे याजा उत्पन्न नहीं की है। जत इगलैंग्ड म राज वन के प्रति जाज भी वड़ी अद्वा है। आधुनिक लोकतानात्रक देशों म दर्गानुगत पत्राप्त को त्राप्त होता है। वराज्य करते हैं लेकिन शासन नहीं। स्वरासिक उपनिवेशा में पत्र पत्र तराज्य के अध्यक्ष के कन्नव्यो का निर्वाह करती है। उत्तरे नाम मान की शासन होता है वेकिन वह स्वय शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती है। उत्तरे नाम य शासन होता है लेकिन वह स्वय शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती।

वास्तिवक कायपालिका से अध झासन की शक्तिया का यथाय रूप म उपयोग करने वाले व्यक्ति या व्यक्ति-समूहस्पी कायपालिका से है। इसे राजनीतिक कायपालिना (Political Executive) भी कहते हैं। इसवण्ड म मित्रमण्डल वास्तिविन नाम पालिका है। वही बिटिश राजा के नाम पर सम्मूर्ण शक्ति का उपभोग करता है। संसुक्त राज्य क्षेमिरका मे राष्ट्रपति राज्य का मी कष्यमा है तथा मुख्य गायपाणिका भी है। ससदीय झासन प्रणाली प्रधान दशा म दो प्रकार की—नाममाम एथे गारत विक—कायपालिकाएँ पायो जाती हैं। नाममान की कायपालिकाएँ पायो जाती हैं। नाममान की कायपालिकाएँ पायो जाती हैं। नाममान की कायपालिकाएँ पायो जाती हैं। मीनमण्डल हारा ही शासन-गाव रिया जाता है और मिनमण्डल राजा के प्रति उत्तरदायी न हारर ध्यवस्थापिशा के प्रति शास्त्राणी होता है।

वास्तविक कायपालिका भी बार प्रकार की हो है है ब्रिटिश, अमिनी, निवस एवं का सीसी राजनीतिक कायपालिकाएँ।

वतानुगत एव निवाचित नायपालिना तथा ॥ममात्र ॥मं भारती स्व वान-पालिका म नेद वर्गीनरण न मित्र बाधारा ना परिणाम है। इंग्ली०० ना वागहरू समार एवं कास का निवाचित राष्ट्रपनि वार्ग ही समात्र सी भार्यपानिका है

¹³ यह ततीय एव चतुन भच गणराज्य न' नाट्यानियां म' गान य म ही दूर्व मास क प्रथम गणराज्य न' राष्ट्रवां ने प्रितात अप । पूनवनियां ले जेते पर्याप्त शक्तियां प्राप्त के । शितात नाच्याय 19 ।

इसके विपरीत, निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति एव 1947 ई के पूव जापान का वसानुकत सम्राट वास्तविक कायपाविका के उदाहरण हैं। नाममात्र एव वास्तविक कायपाविका के अतर का आधार कायपाविका एव व्यवस्थापिका के पारस्परिक सम्बध होते हैं। इसी आधार पर ससदीय एव असमदीय कायपानिकाएँ वर्गीकृत है। ससदीय एव अससदीय कायपाविका

ससदीय छासन प्रणाली को सिन्मण्डलीय एव उत्तरदायी व्यवस्था के नाम से प्रकारते हैं। "अससदीय नायपालिका का अध्यक्षात्मक (Presidential) प्रणाली भी कहते हैं। स्ट्रांग के अनुसार, "सबसीय प्रणाली के अन्तरात मानी व्यवस्थापिका के आ होते हैं और अपने अस्तित्वक के लिए उस पर निमर करता हैं अन कायपालिका के तदस्य व्यवस्थापिका के मी सहस्यहते हैं। " मिन्मण्डल वास्तविक कायपालिका से तो—नाममान एव बास्तविक—कायपालिकाए होती है। मिन्मण्डल वास्तविक कायपालिका के प्रति प्रचाम को कायपालिका होते हैं। मानि नायपालिका स्वति के अध्यक्ष नाममान की कायपालिका होते हैं। मी त्रमण्डल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत एव इंगलेण्ड ससदीय कायपालिका वाले देश है। व्यवस्था त्यक्ष व्यवस्थापिका के अति उत्तरदायी होता है। भारत एव इंगलेण्ड ससदीय कायपालिका वाले देश है। व्यवस्था त्यक्ष वाला के अत्यवस्थापिका के स्वतान होती है। वाने को कायपालिका वाले देश है। वाने कि वाला त्यक्ष वाला होता है। उपान्पित निश्चन अवधि के लिए निवाधित होना है। उत्तर्भ वाला का वाला के साला का मिव्याण का वाला के स्वतान विधान का स्वतान का साला का साला का वाला है। इसी अध्यान म ससदीय एवं अससदीय का साला का वाला के साला का साला का साला का साला का साला का साला है। स्वती अध्यान म ससदीय एवं अससदीय का साला का वाला के साला का साला का वाला है। स्वती अध्यान का साला है। स्वती अध्यान म ससदीय एवं अससदीय का साला का वाला है।

कार्यपालिका की अवधि

सायपालिका की अवधि वा प्रस्त केवल निर्वाचित या मतीनीत कायपातिकाली से ही सम्बिचत है पक्षीक वशानुगत नायपातिकाला का कायकाल तो जीवनपण व होता ही है। नायपातिका का कायकाल एव उसकी पुनिवृक्ति सम्बधी वार्त नाय पालिका प्रमुख की निर्वृक्ति सम्बधी वार्त नाय पालिका प्रमुख की निर्वृक्ति सम्बधी वार्त नाय पालिका प्रमुख की निर्वृक्ति सम्बधी वत महत्वपूष प्रस्त है। विभिन्न देशों म निर्वाचित कायपातिकाला को कायकाल । से 7 वप है। लोकत नीय गणराज्या म नाय पालिका के लम्ब नायकाल को पसद नहीं किया जाता है। इसके मूल मे यह लायका है कि वीपराल तक पदारूव रहने के फलस्वरूप नायपातिका कहीं निर्वृक्ति ना और लगी राजनीतिक व्यवस्था नी स्थापना न कर ल। इसी यस के कारण अधिकाण अभेरिकी राज्या म नायपातिका व पुन निर्वाचित सह है। संपूर्क राज्य अभिरक्ति राज्या म नायपातिका व पुन निर्वाचित सह है। संपूर्क राज्य अभिरक्ति के विप्तृक्ति होते हैं। संपूर्क राज्य अभिरक्ति के विप्तृक्ति होते हैं। संपूर्क राज्य अभिरक्ति के वाप्तृक्ति का नायनात 4 वय है, जबिक कार व जमनी पे राज्यतिका न कायकात 7 वय है। मारतीय राज्यतिका न कायकात 7 वय है। मारतीय राज्यतिका न कायकात 7 वय है। मारतीय राज्यतिक राज्य कि निर्वाचित

¹⁴ Cabinet, Parlimentary or Responsible executive

⁵ Strong Modern Political Constitutions 1963, p 236



या। फास के चतुथ गणराज्य के अनुच्छेद 29 के अनुसार वहाँ का राष्ट्रपति कंवल एक ही बार पुन निर्वाचित किया जा सकता है।

कायपालिकाध्यक्ष के पुन निर्वाचन की ब्यवस्था से नीतिया म तम एव निर तरता बनी रहती है। लेकिन इसके दोप भी है। पुनर्तिर्वाचन की सम्मावना क कारण कायपालिका हढता एव निष्पक्षतापूचक अपने दायित्व का सम्पादन नहीं कर पाती है। सत्य तो यह है कि स्वार्थी राजनीतिज्ञ का कायपातिका के रूप में नियुक्त किया जाना अभिशाप बन जाता है । लेक्नि अमेरिका की माति कायपालिका के कार्य काल को निश्चित करने के भी अपने दौप हैं। ऐसी अवस्या म प्राय देश किसी परिपक्व राजनीतिज्ञ की सेवाओं से उस समय विचत हो जाता है जबकि अनुमव एवं योग्यता की इंटिट से पद के लिए वह प्रत्याशी सर्वाधिक उपयुक्त होता है। लीकॉक का कथन या कि इगलैण्ड मे ग्लेडस्टोन, वेक सफील्ड, सलिसवरी एव लायड जॉज के अनिवाय पद-त्याग को उस समय राष्ट्रीय क्षति माना जाता जबकि वे अपने राजनीतिक जीवन की चरमावस्था पर थे।17

कार्यपालिका की शक्तियाँ एव काय

गेटेल के अनुसार कायपालिका के कार्यों को कूटनीतिक या राजनियक (Duplomatic) सनिक (Military), प्रशासकीय (Administrative), विधायी (Legis lative) एव "यायिक (Judicial) मे वर्गीकृत किया जा सकता है। 18 गानर ने मी यही वर्गीकरण किया है, उन्हान केवल कम बदल दिया है। 19

राजनयक काय

समी देशो म प्राय वदेशिक मामला का सचालन कायपालिका का दायित होता है। राजनयक कार्यों के अ तगत ही वैदेशिक नीति के सचालन सम्ब घी विषय एव काय आत हैं। कायपालिका द्वारा ही विदेशों में राजदूत नियुक्त किये जाते हैं और विदेशी राजदूता की नियुक्ति को अपने देश म स्वीकार किया जाता है। विदेशी सर कारों को मा यता देना, सुरक्षा, व्यापारिक, सास्कृतिक सम्बाधी सभी समभौते एवं सि धर्यां कायपालिका द्वारा ही सम्पादित की जाती हैं।

कुछ देशा में सिंध करने की शक्ति का उपयोग कायपालिका द्वारा व्यवस्था पिना ने सहयोग से निया जाता है। सयुक्त राज्य अमेरिका म सीनेट दो तिहाई बहुमत से सिंघयों का स्वीकृत करती है। गोपनीयता रखने के लिए सिंघ वार्ता से व्यवस्था पिका को पृथक रखा जाता है। प्रथम विश्वयुद्ध-काल म गुप्त कूटनीति या राजनय (Secret Diplomacy) की तीत्र आलाचना की गयी थी।

¹⁷ Leacock Stephen Elements of Political Science, pp 183 184 18 Gettell op at, pp 347 350

¹⁹ Garner op cat Ch XXIII

ग्रेट त्रिटेन में सिंघ करने की शिक्त कायपालिका को प्राप्त है। ब्रिटिश संसद को सिंघ सम्पादन सम्ब की कोई अधिकार नहीं है। इस स्थिति का केवल यह अप-वाद है कि यदि किसी सिंघ को क्रियावित एव प्रमावी होने के लिए किसी विधि की आवस्यन्तता होती है तो संसद को सिंच विधयक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। जमनी म छोटे मोटे समफीतों के अतिरिक्त सभी सिंघया एवं समफीत निम्म सदन के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं। कास म समस्त सिंघया को बीना सदनों के समक्ष स्वीकृति हेतु रखा जाता है। स्विटअरलैंग्ड में 15 वय से अधिक समय के लिए सम्पादित सिंधया को जनमत सम्रह के लिए प्रस्तुत कियं जाने की अनिवाय व्यवस्था है। सपुक्त राज्य अमेरिका म पारस्परिक व्यापार सम्ब ची जैसे अ तर्राष्ट्रीय समफीता को राष्ट्रपति अपने अधिकार मान से ही सम्पादित कर सकता है। योग सभी सिंघयों के लिए सीनेट की स्वीगृत आवस्यक है। अमेरिकी काग्रेस के निम्म सदन— मतिनिधि सदन—को सिंघयों के सम्ब च में केवल अप्रत्यक्ष रूप में ही अधिकार प्राप्त हैं वर्षात् वह किसी सिंध के लिए आवश्यक घनराशि को अस्वीग्रत कर सकता है। सिंघ का कार्यक्ष क्षा में ही अधिकार प्राप्त हैं अपीत् वह किसी सिंध के लिए आवश्यक घनराशि को अस्वीग्रत कर सकता है। सिंपक कार्य

सामा यत कायपालिका का प्रमुख राज्य की सनाओं का मुख्य सेनापित होता है। उदाहरणाथ—अमेरिकी राष्ट्रपति जल, यल एव नम सेनाओं का प्रमुख होता है। मारत का राष्ट्रपति भी प्रमुख होता है। वह सिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है एवं उह पदच्युत करता है तथा सीना की स्वावन्य पिष्ठ होता है। विदिश्व कायपालिका में मुख्य हो घोषणा का अधिकार प्राप्त है। विकित होता है। विदिश्व कायपालिका में युद्ध में घोषणा का अधिकार प्राप्त है। लेकिन "युद्ध सचालन के लिए आवस्यक धन को ससद स्वीकृत करती है। अत व्यवहार में युद्ध की घोषणा के लिए अवस्यक धन को ससद स्वीकृत करती है। से सुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध की घोषणा का अधिकार किया को है लेकिन राष्ट्रपति विद्याल मीति एव राजनय के सचालन से ऐसी स्थित उत्पन्न कर सकता है कि युद्ध सिनाय एव आवस्यक हो जाय। ततीय एव चतुय फेन गणराज्यों म युद्ध की घोषणा करने के लिए दोनों सदना की स्वीकृति आवस्यक थी।

द्ध-काल मे अमेरिकी राष्ट्रपति को मुख्य शनापति होने के कारण सनिक विधिया के किया वधन का अधिकार प्राप्त हो जाता है तथा मुद्ध-काल म बहु नागरिक अधिकारों एवं बन्दी प्रत्यक्षीकरण के अधिकारों के निलम्बित कर सकता हैं राष्ट्रपति उन अनेक विधियों को भी निलम्बित कर सकता है जो सनिक अधि-कारिया की दृष्टि सं महत्वहीन हा। इन आगाओं ने उल्लंघन के लिए वह व्यक्तिया

²⁰ Gettell op est, p 348

²¹ Garner op cat p 654

को दण्डित मी कर सकता है। 28 द्वितीय विष्वयुद्ध-काल म अमेरिकी कांग्रेस ने अनेक विधिया पारित की यी। अनेक देशों की कायपालिकाओं को सकट काल या युद्ध काल में ब्यापक शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। मारतीय केंद्रीय मित्रमण्डल को ब्रिटिश मित्रमण्डल के समान ही युद्ध सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हैं।

प्रशासकीय काव

कायपालिका का प्रमुख दायित्व व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित विधिया को किया वित करना होता है। इस हेतु कायपालिका अधीनस्य प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति करती है, एव उनकी सेवा की धावें निर्धारित करने तथा पदस्पुत करने एव निरोक्षण सम्ब भी अधिकार भी उसे प्राप्त होते हैं। विभिन्न शासकीय विभागों की उसके द्वारा स्थापना की जाती है एव उनका सगठन किया जाता है। जैसे, सगुक्त राज्य अमेरिका सहस राज्यों म कायपालिका की प्रवासकीय शक्ति पर व्यवस्थापिका अधीत कांग्रेस के उन्ध सदन का नियालय होता है। अमेरिकी सीनेट दो तिहाई बहु मत से अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की गयी नियुक्तिया को अनुसीदित करती है। समरणीय है कि अधिकारियों को पदच्युत करने की शक्ति केवन राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। समी देशा म सामा यत्त बहुसस्यक प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति लोक स्था आयोगों के अधीन प्रतियोगी परीक्षाओं के साध्यस से की जाती है।

अमेरिकी राष्ट्रपति की नियुक्ति करने की शक्ति का सम्बन्ध केवल उच्च राजनीतिक, यायिक एव सैनिक पदाधिकारिया से ही होता है। वैकोस्लोबाकिया म मुख्य कायपालिका विद्वविद्यालयों के प्रावार्यों की भी नियुक्तिकरता है। स्विट्जरलग्ड मेनिय प्रशासकीय अधिकारिया की नियुक्ति ध्यवस्थापिका द्वारा की जाती है। सपुक्त राज्य अमेरिका के घटक राज्या में अनेक सावजनिक पदा पर नियुक्तियाँ जनग निर्वाचन की रीति स करती है। विधिया के किया वयन हेतु कायपालिका द्वारा जरेर नियमा एव उपनियमो या निर्माण किया जाता है।

प्रधासकीय चीक्त को आंतरिक एवं नुष्ठ दत्ता में गृह सक्ति की सना है। जास में विधिया के त्रियानयन एवं प्रधासन में भेद किया जाता है। कास में विधिया के त्रियानयन एवं प्रधासन में भेद किया जाता है। विधिया के त्रियानयन को कायपासिका के राजनीतिक या सासकीय काम (political or governmental functions) एवं द्वितीय अर्थात प्रधासन को प्रधासकीय काय की समा प्रदास की जाती है।

विधायी काय

विधि निमाण म सायपालिका महत्वपूण भूमिका अदा करती है। समदीय प्रणाली म कावपालिका विधि निर्माण म यथायत ससद का नतृत्व करती है। मीत्र

²² Garner op at p 655

मण्डल द्वारा ही व्यवस्थापिका के अधिवेशन आहत, स्थगित एव समाप्त किये जाते हैं। कायपालिका द्वारा ही व्यवस्थापिका के प्रथम सन का उदघाटन किया जाता है। कायपालिका व्यवस्थापिका को विघटित करके नवीन चुनावा की माग कर सकती है। विधियों को प्रस्तावित करना एवं उनको सदन में पारित कराना सम्बन्धित मित्रया का दायित्व होता है। अध्यक्षात्मक प्रणाली म कायपालिका की विधि-निर्माण सम्बाधी शक्तिया सीमित होती हैं। इन देशा में वह ससदीय कायपालिका की भाति ससद का नैतत्व नहीं करती। व्यवस्थापिका के अधिवेशन स्वत नियमित रूप स होते हैं। अम रिकी राष्ट्रपति विधि-निमाण से अप्रत्यक्ष रूप से ही सम्बर्धित होता है। वह अम-रिकी कांग्रेस के नाम स देश भेजता है और इन स देशा के माध्यम स ही वह कांग्रेस स विभिन्न विभियों के निर्माण का प्रस्ताव करता है। विभिन्न प्रस्तावों की स्वीकृति या अस्वीकृति काग्रेस पर निभर करती है। "गणत त्रो मे कायपालिका को विशिष्ट सामलो पर विचार हेत सकट-काल मे ससद के विशेष अधिवेशन आहुत करने का अधिकार अनिवायत प्राप्त होता है। सामा यत सविधान द्वारा ही व्यवस्थापिका के सन्नारम्म सम्बंधी व्यवस्था की जाती है और कार्यपालिका द्वारा ससद को आहत करन की व्यवस्था नहीं की जाती है।^{?) 3} संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली एवं ब्राजील के सम्बाध म यही सत्य है।

सस्वीय देशों में ससद के प्रत्येक प्रथम सब म राज्याच्यक्ष अपने मापण म मिनमण्डल की नीतियां का उल्लेख करता है। अध्यक्षात्मक प्रणाली म सस्वीय देवा नी माति राष्ट्रपति कं मापण की कोई व्यवस्था नहीं हाती। सानर के अनुसार, "राज तंनीय देशा म कायपालिका को व्यवस्थापिका के सन्ना का मविष्य के लिए स्थितत करने का अधिकार सिवधान द्वारा प्रवान किया गया है। सिकन गणराज्या म इस प्रकार के अधिकार का अमाव होता है। सस्वीय देशा म कायपालिका कुछ परिस्पितियों में व्यवस्थापिका के अधिवेशन का स्थितत कर सकती है।" अप्रधारमक देशा में संयुक्त राज्य अमरिका की माति कायपालिका का विधानमण्डल के सन्नों को स्थितिय करने का अधिकार केवस दोना सदना म विवाद उत्पन्न होन की अवस्था म ही प्राप्त होता है।

कार्यपालिका सकट काल म अध्यादेश (Ordmance) जारी कर सकती है। जध्यादेशों का विधानमण्डल द्वारा निर्मित विधियों के समान ही महत्व एव प्रमाय होता है। कायपालिका-प्रमुख को निषेषाधिकार (Veto) की उत्तायपार पारिक प्राप्त होती है अर्थान् वह विधानमण्डल द्वारा पारित विधिया का अपन हस्ताधर प्रयान करने से अस्वीकार कर सकता है या पुन विचार हेतु उत्त पुन सदन को वापउ

²³ Garner op cst, p 660

²⁴ Ibid

486 | आधुनिक शासनताथ

भेज सकता है। विधानमण्डल द्वारा पारित विधियों नायपालिनाध्यक्ष द्वारा स्वीहत किये जाने पर ही विधि बनते हैं। ग्रेट ग्रिटन म नाउन ना पूण निषेषाधिकार प्राप्त है। ग्रिटिश ससद उसे समाप्त नहीं कर सनती। लेकिन यह कवल सिद्धान्त म ही सर है। ग्रिटिश ससद उसे समाप्त नहीं कर सनती। लेकिन यह कवल सिद्धान्त म ही सर है। ग्रिटिश सपद व्यवस्था के विकास के साथ भाउन द्वारा दीधकाल स निषेषा थिकार का प्रयोग नहीं किया गया है। फलस्वरूप वह निष्प्रमावी हा गया है। वगत का मत है कि दार्यलण्ड के सिवधान का यह मौतिक विद्वात है कि प्राउन किसी अधिकार के प्रयोग न करने के कारण उसे सो नहीं देता है। वत नाउन का प्राप्त निषेधाधिकार प्रयोग के अभाव म निष्प्रमावी नहीं हो सकत। यह केवल सर्वानिक स्थित है। लावेल (Lowell) ने उन सम्मावित परिस्थितिया का मी उल्लेख किया है जब नाउन हारा निष्धाधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन व्यवहार में काउन द्वारा निष्धाधिकार स्वाह्म स्वाह्म से प्रयोग नहीं किया गया है।

सयुक्त राज्य अमेरिका मे राष्ट्रपति को प्राप्त निर्पेधाधिकार पूण नहीं है। कामेस के दोनो सदन यदि पुन अपन दो तिहाई बहुमत से सम्बिध्य विधि को पारित कर देते है तो राष्ट्रपति का निर्पेधाधिकार निष्ठमावी हो आता है। अमेरिकी राष्ट्रपति को निर्पेधाधिकार निष्ठमावी हो आता है। अमेरिकी राष्ट्रपति को निर्पेधाधिकार के कारणा का भी उत्तसे करना पडता है। निर्पेधाधिकार को उद्देश यह है कि व्यवस्थाधिका द्वारा होझता मे पारित व्यविकेशिय विधियो को पारित होंने से रोका जाय। हैमिस्टन (Hammilton) का मत या कि निर्पेधाधिकार के अमाव म कायपालिका नमत सत्ता विहोन हो जाती है। निर्पेधाधिकार कायपालिका के लिए बाल का काय ही नहीं करता अधितु दलीय भावना एव द्योझता तथा समुर्वित विचार विभयो के अभाव म पारित विधियो पर पुन विचार के अवसर प्रवान करता है। निर्पेधाधिकार के द्वारा कायपालिका व्यवस्थापिका से अपने निषय पर पुनर्विवार करते को कहती है।

तृतीय एव चतुष फ्रेच गणराज्या मे कायपालिका को आशिक निर्वेषाधिकार (suspensive velo) प्राप्त था जिसका उद्देश्य फ्रेच ससद द्वारा पारित एव राष्ट्रपृष्ठि द्वारा अस्थीकृत विधिया पर पूर्नावचार की व्यवस्था करना था। अस्वीकृत विधिया की यदि पुन सामा बहुमत हे फ्रेच विधानमण्डल द्वारा पारित कर दिया जाता तो वे राष्ट्रपृति की अस्बीकृति के बावजद भी विधि वन जाती थी।

"याधिक काय

कायपालिका द्वारा अनेक यायिक काय भी सम्पादित किये जात है। समी स्तर्र के यायाधीयों को उसके द्वारा नियुक्त किया जाता है और अयोग्य एव प्राट्ट याया धीशा की परच्युत किया जाता है। कुछ देशों में उच्च यायाधीयों को विधानमण्डत हारा प्रस्ताव पारित करके प्रायना करन पर कायपालिका परच्युत कर सकती है। सनी देशों नी कायपालिका के प्रमुखा या अध्यक्षा को यायालय द्वारा दण्डित अपराधिया को क्षमा करन, दण्ड को कम करने अथवा स्थागत करने के अधिकार प्रान्त होते हैं। विद्रो-हियों को आधिक व सामूहिक क्षमादान प्रदान करने का अधिकार भी उसे होता है। दिटेन तथा भारत म क्षमादान की शक्ति का प्रयोग मुहमानी के परामश पर किया जाते हैं। समुक्त राज्य अमेरिका के अनेक राज्या में क्षमादान के सम्बाध में राज्यपाता को परामदा देन के लिए परामश्रदायो परियद होती है। लेकिन महाभियोग के जप-राधिया को कायपालिका क्षमा प्रदान नहीं कर सकती। अमेरिकी राष्ट्रपति को जप राधी को दण्ड देने के पश्चात या पूत क्षमा प्रदान करने का अधिकार प्रान्त है।

लोकतानिक देशों में शासन के विभिन्न विभागा को प्रशासन सम्बंधी नियम एवं उपनियम बनाने के अधिकार होते हैं। इन नियमों के अतगत कायपालिका द्वारा निणय भी दियं जाते हैं। अतः प्रशासकीय विधि के अधीन कायपालिका को अद्व-

'यायिक शक्तिया प्राप्त होती हैं।

ससदीय कार्यपालिका

ससदीय देशों में वास्तविक कायपालिका अर्थात मिनमण्डल विधिक हिष्ट से व्यवस्थापिका के प्रति अपने कार्यों एव नीतिया के लिए प्रत्यक्षत उत्तरदायी होती है। नाममान की कायपालिका अर्थात नाउन या राष्ट्रपति पुणक्ष्पेण अनुत्तरदायी होत है। राष्ट्रपति या काउन के प्रत्येक कार्य के लिए कोई न काई म नी उत्तरदायी होता है।

ससदीय कायपालिका की परिभाषा गानर के शब्दा म निम्नत है

"मिनमण्डलीय सरकार वह पद्धति है जिसम यथाय कायपालिका—मिनमण्डल या म नीगण—अपनी राजनीतिक नीतियो या कार्यों के लिए प्रत्यक्षत या विधिक रूप के व्यवस्थापिका अथवा उसके एक तदन (प्राय कांकप्रिय सदन) के प्रति और अन्तिम रूप में निवाचका के प्रति उत्तरदायी होती है। उपाधिशारी या नाममात्र की काय पालिका जो राज्य का प्रमुख होती है, किसी के प्रति यी उत्तरदायी नहीं होती।

ससदीय कायपालिका की मुख्य विशेषताएँ निम्न हैं

(1) दो प्रकार की कायपालिकाएँ—ससदीय प्रणासी म दो प्रकार के प्रमुख होते हैं नाममान का अध्यक्ष (nominal head) एव यथाथ कायपासिका (real executive)। नाममान की कायपासिका वशानुगत या निर्वाचित होती है। इसकी नाममात्र की शक्तिया प्राप्त होती है। यह राज्य एव शासन दोना का हो अध्यक्ष होता है। यथाथ कायपासिका—मित्रमण्डल—इसीकेनाम परसम्भूष शक्तिया नाप्रयोग करती है। यथाय कायपासिका—मित्रमण्डल—इसीकेनाम परसम्भूष शक्तिया नाप्रयोगित के शासना के क्या सभी सदस्य उसके अधीन होत है। नाममात्र की नायपासिका केवा उपाधिवारी प्रमुख होता है। वह राज्य की प्रतिष्ठा एव यरिमा का प्रतीक होता है। उदाहरणाय, अगलण्ड की रानी वहाँ की नाममात्र की प्रमुख है, वास्तियक नायपासिका शक्ति इसलण्ड के मित्रमण्डल में निहित है। मारत ने राष्ट्रपति की स्थित

²⁵ Garner op cit, p 296

भी ब्रिटिश सम्राट के ही समान है। भारतीय सविधान द्वारा सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति में अधिष्ठित है लेकिन मित्रमण्डल में सदस्य उसको सहायता एव परामश हुतु नियुक्त किय जाते है जो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप स उत्तरदायी हात है। अत भारतीय राष्ट्रपति नाममात्र के कायपालिका है। वे द्वीय मित्रमण्डल ययाय या वात्तविक कायपालिका है। नाममात्र की कायपालिका राज्य का अध्यक्ष है जबिक कायपालिका सक्ति का प्रयोग उसके नाम पर मित्रमण्डल करता है। वास्तविक या यथाय काय पालिका निर्वाचित होती है एव अपने सभी नायां कि लिए विधानमण्डल कप्रति उत्तर वायी होती है।

- (2) कायपातिका एव ब्यवस्थायिका से घिनिष्ट सम्बंध-सारीय प्रणाली में सिक्त पुषकरण का सिद्धारा मान्य नहीं है। यथाय कायपालिका-मिन्न-पिर्य-कि सं सदस्य ब्यवस्थायिका के सदस्य होते हैं। सामान्यत विधानमण्डल के निम्न पदन के बहुमत दल को मिन्न-पिर्य के निर्माण का अधिकार होता है। बहुमत दल के नती को प्रधानमन्त्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। विश्वी ब्यक्ति को जब मनी नियुक्त किया जाता है, उस समय उसके लिए व्यवस्थायिका का सदस्य होना आवश्यक नहीं होता। लेकिन ऐसे ब्यक्तिया को एक निश्चित समय के मीतर विधानमण्डल का सदस्य हो जाना चाहिए अयथा उह मन्त्री पद से हटना पडता है। मिन्नपडल के सदस्या द्वार विधानमण्डल को सदस्या द्वार विधानमण्डल को सदस्या द्वार विधानमण्डल को सदस्या द्वार विधानमण्डल को नेतृत्व करता है। क्षान्य चासन के ब्यवस्थायिक। एव काय पालिका अर्था में पारस्थिरक सहनोग सम्यव होता है। क्षा
- (3) सिनमण्डलीय उत्तरवायित्व—संसदीय प्रणाली के जातगत कायपातिकां (मिनमण्डल) व्यवस्थापिका के प्रति अपने कायगें एव गीतियों के लिए उत्तरदायी होंगी हैं। इसका जम है कि सिनमण्डल उसी समय तक पदास्क रह सकता है जब तक कि वे व्यवस्थापिका का विस्वास प्राप्त होता है। मिनमण्डल के विस्त्व अविश्वास का प्रस्ताव गारित होने या किसी विधेयक या बजट के अस्थीकृत होने पर मिनमण्डल को पदस्याग करना पड़ता है। इसके अविश्वक सा क्ष्य के अस्थीकृत होने पर मिनमण्डल को पदस्याग करना पड़ता है। इसके अविश्वक्त स्वाप्त के प्रस्त पूछकर अवधा निवास प्रस्ता के सा प्ता के सा प्रस्ता के सा प्रस्ता के सा प्रस्ता के सा प्रस्ता के सा
- (4) सामूहिक उत्तरवायित— इतका अय यह है कि सभी मानीनण व्यवस्था पिका के प्रति समुक्त या सामूहिक रूप से उत्तरदायी होत हैं। नीति निर्धारण के समय समी मित्रयों को अपनी राय व्यक्त करने का अवसर होता है। एक बार निजय ही जार पर हर गंत्री विधानमण्डल एवं जनता के समझ उस नीति का समझन करने के विष् वाध्य है, मले ही वह व्यक्तिगत रूप से उस निजय से सहमित गरखता हो। अत व्यवस्थापिया के समझ सभी सरस्य मित्रमण्डल की नीतिया के लिए उत्तरदायी होत है। यदि वोई मानी मित्रमण्डल के नित्य रखता हो। अत व्यवस्थापिया के समझ सभी सरस्य मित्रमण्डल को नीतिया के लिए उत्तरदायी होत है। यदि वोई मानी मित्रमण्डल के निजय सं अतहमति यहता है तो ऐसी जनस्या में

उसे पदस्याग कर देना चाहिए। किसी एक विभाग के मंत्री द्वारा यदि कोई भूल की जाती है तो सम्पूर्ण मित्रमण्डल उसके लिए उत्तरदायी होता है और सभी मंत्री अपने पद से स्वागण्य दे देत हैं। अल सभी एक साथ दूवले और एक साथ तरत है (They swim and sink together)। यह सम्मव है कि किसी अयोग्य सुरक्षा मंत्री की भूल के लिए सम्पूर्ण मित्रमण्डल नो स्वागण्य देना पड़े। लेकिन इसका यह अथ नहीं है कि किसी मंत्री की व्यक्तिगत शुदि एवं अस्ट आवरण के लिए भी सम्पूर्ण मित्रमण्डल को पद्याण करना पड़ेगा। अपनी व्यक्तिगत भूत के लिए केवल सम्बंधित मंत्री की ही लाग पत्र देना पड़ता। अपनी व्यक्तिगत भूत के लिए केवल सम्बंधित मंत्री की ही लाग पत्र देना पड़ता। विश्व मित्रमण्डल से स्वत्य पत्र तो की ही बजट के रहस्यों के पूत्र प्रकाशन के लिए ब्रिटिश मित्रमण्डल से स्वागपत्र (1947 ई) देना पड़ा पा। बाँ सम्बंधित होने के कारण अपने पद सम्बंधित शोभ को बी सित्रमण्डल से स्वागपत्र देना पड़ा था। बाँड सम्बंधित एवं बेलिको को भी मई 1973 ई म ससी प्रकार की चारित्रिक झस्टता एवं सुर्वरियों के साथ सम्बंधित होने के कारण भित्रमण्डल ने हटना पड़ा था।

(5) प्रधानमात्री द्वारा नेतत्व—प्रधानम त्री मित्रमण्डल का वास्तिषिक मैता या प्रमुख होता है। वह मित्रमण्डल के सदस्यां का चयन करता है, समी विभागों के कार्यों का निरीक्षण करता है तथा उनके मध्य समाचय स्थापित करता है। यदि किसी मात्री के कार्यों से वह अस पुष्ट होता है तो सम्बचित मात्री से रयायपत्र की माग कर सस्ता है या उस पदध्युत कर सकता है। वह मित्रमण्डल की बठकों की अध्यक्षता करता है। विधानमण्डल म वह बहुमत दल एवं शासन का नेता और प्रवक्ता होता है। लासकी के शब्दों मं, 'उसकी स्थित मित्रमण्डल के जम्म, जीवन एवं मत्यु की हैं जिस की माग करने की माग करने का भी अधिकार होता है।

ससदीय कायपालिका के गुण

- (1) कायपालिका एव व्यवस्थापिका के मध्य पूल सामजस्य एव सहयोग होता है। विकासी के अनुसार, "यह पढ़ित उत्तरवाधित्व, निर्देशन एव प्रमुख की एकता का समयन करती है। इसम झासन कि कि निर्देश मध्य सपय असम्मय हो जाता है। 'कायपालिका एव व्यवस्थापिका में एक ही दल की प्रमुखता होने स इसम मत-मेद एव गतिरोध की सम्मावना नहीं होती।
- (2) कायपालिका के स्वेच्छाचारी एव अनुत्तरदायो होने की सम्मावना नही होती। मिनमण्डल की ट्रांट्ट सदव ही जनमत पर होती है।
- -- (3) यह प्रणाली पर्याप्त नमनीय है। अवसर के अनुरूप बेजहोट र अनुसार, जनता सासन का चुनाव कर सकती है। प्रथम विस्वयुद्ध गाल मे एमलण्ड मे ऐस्किप्स (Asquith) के स्थान पर लायड जाज (Lloyd George) की बिना निसी कठि

नाई के प्रधानम ती चुन लिया गया था। इसी प्रकार चर्चिल को चेम्बरलन के स्थान पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रधानम ती नियक्त किया गया था।

- (4) इस पढित का शैक्षाणिक मूल्य भी है। सुदृढ एव समिटत दलीय व्यवस्य के अभाव म इस पढित की सफलता सिदम्य होती है। 'दलीय प्रणाली एव उसरी कायपढित, प्रचार, निर्वाचन आदि से जनता की प्रयाप्त राजनीतिक शिक्षा एव वेतना प्राप्त होती है। के लेकिन इसे हम केवल ससदीय प्रणाली की ही विशेषता या गुण नहीं मान सकते।
- (5) ससदीय प्रणाली मं कायपालिका एव व्यवस्थापिका के मध्य सामजस्य आवश्यक होता है। इससे शासन-काय को शीध्रता एव विश्वासपूवक सम्मादित किया जाता है तथा कायपालिका को प्रत्येक विषय मं शीध्र निषय सेन एव निश्चित ततापूवक अपने यापिता को सम्पादित करने में सहायता मिलती है। ससदीय कायपालिका के होग्र
- शक्ति पृथवकरण के सिद्धा त के अनुसार कायपालिका एवं व्यवस्थापिका का एकीकरण नागरिक स्वत नता की इंटिट से घातक होता है।
- (2) ससदीय प्रणाली दलीय सरकार होती है। इसके लिए दलीय पद्धति एक कठोर दलीय अनुशासन का विकास आवश्यक होता है। अत ब्राइस के अनुसार, "यह पद्धति दलीय मावना को बढावा देती है। राष्ट्र के समक्ष महत्वपूण नीति सम्बधी प्रकान होने पर भी (राजनीतिक) पदो के लिए दला म सदैव समय होता रहता है।'" विरोधी दल द्वारा सदैव ही शासन की नीतियों का केवल विरोध के लिए विरोध किया जाता है। अत इस पद्धति के अतगत समय एव शक्ति का अपकाकृत अधिक अपव्यव होता है। वत इस पद्धति के अतगत समय एव शक्ति का अपकाकृत अधिक अपव्यव होता है।
- (3) सिजबिक के अनुसार इस प्रणाली का प्रमुख दोष यह है कि मिनया की बहुत सा समय केवल विधि निमाण में ही व्यतीत हो जाता है। फलस्वरूप व अपना पूण ब्यान एवं समय कायपालिका के दायित्वा के सम्यादन भ नहीं दे पाते हैं।
- (4) ससदीय प्रणाली म शासन म स्थायित्व का जमाव होता है। में त्रमण्डल का कायकाल व्यवस्थापिका की कृषा पर निभर करता है। दलीय अनुशासन एव सा ठन के कारण यह दाप कम होता जा रहा है परन्तु बहुदलीय पदित प्रधान देशा में यह दीप अधिर स्पष्ट है और उसके परिणाम घातक है। फास के चतुन गणराज्य म मिनण्डला मा लावकाल अल्प कल्प रहा था। बहुदलीय पदित के कारण मा स मा निमण्डला में लावकाल अल्प कल्प रहा था। बहुदलीय पदित के कारण मा स पाजनीतिक अस्पिरता व्यापक रूप स फल गयी थी जिससे मुक्ति नवीन (फास पा पनम गणराज्य) सविधान व निमाण से ही प्राप्त हई है।

Gilchrist Principles of Political Science, 1930, pp 243 44
 Bryce Modern Democracies, Vol II, 1929, p 512

(5) ससदीय प्रणाली का एक दोप यह भी है कि सकट काल में कायपालिका अपेक्षाकृत सीघ्र निणय करने में असमय रहती है। डायसी के अनुसार इस व्यवस्था के दो प्रधान दोप है। प्रथम, यह वस्तुत दलीय धासन है अर्थात ऐसे व्यक्तियों का शासन होता है जो दल के सदस्य होने के कारण नेतृत्व प्राप्त करते हैं, दल के कारण सत्ता में आते हैं तथा उनकी नीतिया दलीय रंग में रगी रहती हैं। असदीय कायपालिका बहुल कायपालिका (plural executive) है। मित्र मण्डल एक समिति है। अत यह युद्ध एव राष्ट्रीय सकट से कमजोर सिद्ध होती है। द्वितीय, मित्र मण्डल सबद के हाथा में खिलीना वन सकता है।

ससदीय शासन की प्रवान आलोचना यह है कि कठोर दलीय अनुशासन के कारण मित्रमण्डल का अधिनायकत्व स्थापित हो जाता है। स्वामी सेवक एव सेवक स्वामी निग गया है अर्थात सबद मित्रमण्डल की अनुचर वन गयी है। प्रधानमानी की स्थित मित्रमण्डल में के ब्रीय होती है। जत सास्की का यत या कि मित्रमण्डल के हाथों में विधायों पूर्व कायपालिका शक्तियों को ब्रीविस्था वयक्तिक स्थत तता एव अधिकारों की हिण्ट में घातक है। उपरोक्त आलोचना तकसगत नहीं है। ससदीय प्रणाली आधुनिक प्रतिमिधमूलक प्रजात न म सर्वाधिक थेप्ट पद्धति है एवं सिडनी सो का यह कथन सत्य है कि इस प्रणाली के अत्यगत लोकत नीय सिद्धान की सर्वाधिक रखा होती है।

अध्यक्षात्मक कार्यपालिका

अससदीय कायपालिका का अध्यक्षारमक कायपालिका भी कहते हैं। स्ट्राग के अनुसार कायपालिका हमेशा ही किसी के प्रति उत्तरदायों होती है, चाहे तो सबद के प्रति । एक निरिक्षत समय के परकात जनता के प्रति । "यदि कायपालिका निरिक्षत अविष के परकात निर्वाद अपना के परकात निर्वाद अपना के परकात निर्वाद अपना के परकात निर्वाद अपना के उत्तर हाथा है तो है एव ससदीय मित्रा से उत्तर हाथा नहीं जा सकता तो उसे अससदीय या स्विप् (Fixed) कायपालिका कहते। ।" व स्त्राव के स्वेत हुए कहा है कि "अध्यक्षारमक प्रणाली के अत्यग्त सिद्धार वा पर के लिए चुना जाता है। " अप अध्यक्षारमक प्रणाली के कायपालिका अपने कायफाल के सम्ब से में वैद्यान हरिंद से स्वयस्था पिका से स्वात ने होती है एव अपनी राजनीतिक नीतिया के लिए व्यवस्थापियां में प्रति उत्तरदायी नहीं होती। इसकी मुख्य विद्यापताएँ इस प्रकार है

²⁸ Dicey Cabinet v Presidential Government, cited by Garner op cit, Footnote No 23, pp 390 91

²⁹ Strong op est p 74 30 Ibid , p 261

- 492 | आधुनिक शासनतात्र
- (1) अध्यक्षात्मक प्रणाली म नाममात्र (Titular) एव वास्तविक (Real) कायपालिकाओ वा भेद नही होता। वायपालिका वा अध्यक्ष नाममात्र वा अध्यक्ष नहीं होता। सविधान द्वारा प्रदक्त सभी दाक्तियो का प्रयोग उसी के द्वारा किया जाता है। यही यथाय कायपालिका होती है। राज्य तथा कायपालिका का अध्यक्ष एक ही व्यक्ति होता है।
- (2) इस प्रणाली क अत्यात कार्यपालिका व्यवस्थापिका व प्रति उत्तरवाणे नहीं होती और न उसकी सहायता पर ही निमर करती है! उदाहरणाय, अमरिषे राष्ट्रपति काग्रेस के प्रति उत्तरदायों नहीं होता है और न उसका कायकाल हो व्यवस्था पिका के सहयाग पर निमर होता है। वह चार वय अथात् निश्चित काग्रकाल क तिए निवाचित होता है।
- (3) अध्यक्षात्मक प्रणाली के अन्तगत कायपालिका जनता द्वारा निश्चित कायकाल के लिए चुनी जाती है और उसे पद क दुरुपयांग के अपराध पर महामियाग द्वारा ही पदच्युत किया जा सकता है ।

(4) कायपालिका अर्थात राष्ट्रपति द्वारा व्यवस्वापिका को मग नहीं किया जा सक्ता । व्यवस्थापिका का कायकाल और उसकी शक्तियाँ एव अधिकार मी सर्वि धान द्वारा निश्चित होते है ।

(5) अध्यक्षारसक प्रणाली में वाक्ति पृथवकरण के सिद्धात को मायता है।
गमी है, फलस्वरूप कायपालिका एव व्यवस्थापिका की शक्तिया पृथक-पवक होती है।
कायपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं। उदाहरणाथ, अमरिका
राष्ट्रपति एव उसके मा निगण्डल के सदस्य कांग्रेस के किसी सदस्य कं सदस्य नहीं हाँ
और यह भी आवस्यक नहीं है कि व एक हो राजनीतिक दल के सदस्य हो या बहुण्य
दल के ही सदस्य हा। वे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं एव उसके प्रसाद प्यत्त
ही पदाव्ह रहते हैं। वे उसके म भी नहीं अभितु सचिव (Secretary) होते हैं।
इगलैण्ड के मन्तिया की माति वे ससतीय नेता नहीं होता।

ससवीय प्रणाली में सिद्धा तत व्यवस्थापिका या ससद की सर्वोच्चता होती है। इतक काथानिका ससद के अधीन होती है एवं उसी के प्रति उत्तरदायी होती है। इतक विषयित, अध्यक्षात्मक प्रणाली में कायपालिका एवं व्यवस्थापिका एक दूसर के समान होती है। दोनों का कायकाल निश्चित एवं धक्तियाँ निर्धारित होती है। दोना एक दूसरे से नह । दोनों के कायकाल निश्चित एवं धक्तियाँ निर्धारित होती है। दोना एक दूसरे से नह । दोनों के कायकाल निश्चित होती है और एक दूसरे के निर्धारित नहीं करती।

(1) सस्दीय प्रणाली की तुलना म अध्यक्षात्मक कायपालिका अधिक स्पिर होती है। कायपालिका निश्चित समय के लिए जनता द्वारा निर्वाचित होती है। वह व्यवस्थापिका द्वारा हटाई नहीं जा सकती है और न सस्दीय कायपालिका की मीति विधानमण्डल का मग करने का उस अधिकार प्राप्त है। (2) अध्यक्षात्मक कायपालिका अपक्षाकृत अधिक कायकुशल होती है। एक व्यक्ति म सक्ति निहत होने के कारण निणय शोझतापूर्वक किय जा सकते है।

(3) मित्रयों को व्यवस्थापिका से कोई सम्बंच न होने के कारण वे अपना अधिकाधिक समय प्रशासन को देते हैं।

(4) विधानमण्डल म दलीय अनुशासन अपेक्षाकृत कम होता है ।

(5) अध्यक्षात्मक प्रणाली के अन्तगत राष्ट्रपति के पुन निर्वाचन की व्यवस्था होती है। अस नीतियो म कम एव स्थायित्व की सम्मावना वनी रहती है। साथ ही एक व्यक्ति के अधिनायकत्व की स्थापना का यथ नही रहता। शक्ति पुयवकरण पर आधारित होने के कारण शासन की सम्यूण सत्ता किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह म केंद्रित नहीं हो पाती।

अध्यक्षात्मक प्रणाली के दोप

(1) अध्यक्षारमक पद्धति म राष्ट्रपति के निरकुश होने की सम्मावना होती है। जनप्रतिनिधिया—विधानमण्डल—के नियन्त्रण से वह स्वत च होता है। उसका कायकाल निश्चित होता है एव उसे उसके पद स उसके कायकाल के मध्य म सुटाया नहीं जा सकता। एस्मिन के अनुसार यह प्रणाली निरकुश, अनुसरायी एव स्वतरनात होती है। में सविधान के अनुसार अध्यक्षारमक कायपालिका अपने कायकाल म अपनी इच्छा नुसार सामत कर सकती है और जब तक उसका आवरण आपत्तिजनक नहीं होता वह पदच्युत नहीं क्या जा सकता। वह अनुसरदायी इस अथ म है कि वह व्यवस्थानिक के प्रति उत्तरदायी नहीं है। गानर के अनुसार अधरिकी कंपिस राष्ट्रपति की निया कर सकती है, उसे परिस्थितयों के अनुकुत सिक्या देने से इकार कर सकती है, उसके नियेधाधिकारों को अमा य ठहरा सकती है, लेकिन वह सविधान प्रवत्त उसकी पितियों के कम या सीमित नहीं कर सकती। है

(2) अध्यक्षारमक प्रणाली के अन्तगत कार्यणालिका एव व्यवस्थापिका म आप दिन गतिरोध उत्पन होते रहते हैं। कायणालिका द्वारा व्यवस्थापिका म विधेयक प्रस्तावित नहीं किये जा सकत। कायणालिका जब एक दल की होती है और व्यवस्थापिका म दूसर दल का बहुमत होता है तो एकी अवस्था भ धामल ना काय मुचाई रूप स नहीं चल पाता है और एक दूसरे पर उनके द्वारा वापारापण विच जात हैं। दोनो ऐसी स्थित म एक दूसरे के विरोधी वन जाते हैं। बाइस का क्यन है कि शांकि पुष्पकरण के प्लदस्वरूप स्वामाणिक एक त्यार्थ के प्रतर्वह अलगाव उत्पन्न हो जाता है। कायपालिका एव विधानमण्डत दोना एक दूसर पर उत्तरदायित्व पानन

32 Garner op at, pp 395 96

³¹ Esmein Driot Constitutional p 419 cited by Garner op at (5th edn 1909) p 395

का प्रयत्न करते हैं एव समय-समय क्षेत्राधिकार सम्बाधी विवाद भी उत्पत्र हो रहते हैं।

(3) अध्याक्षात्मक प्रणाली की निधि निर्माण प्रक्रिया भी दोपपूण होती है बहु-समिति व्यवस्था (Multiple Committee System) की प्रधानता होने के कार विधि निर्माण मे विलम्ब, अस्पष्टता एव पारस्परिक विरोध स्वामाविक होता है।

विलोबो के अनुसार अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के दोप निम्न है--इस पद्धि

मे शासन सत्ता एव उत्तरदायित्व कई अगो मे विमाजित होता है। इनम एक दूसरे वे प्रति ईर्ष्या होती है। परस्पर सहयोग कठिन हो जाता है। शासन प्रणाली अपेक्षाइट अपरिवतनशील होती है। शासन के विभिन्न अभी मे विवाद स्वामाविक हाते हैं जिनक निणय यायपालिका ही कर सकती है।³³ ब्रिटिश यायशास्त्री वेजहोट³⁴ ने अध्यक्षा त्मक प्रणाली के दोषो को निम्न शब्दों म व्यक्त किया है "इस प्रणाली म कायपालिक पगु बन जाती है क्योंकि वह उन विधियों को पारित करान मं असमय होती है जिनकी उसके द्वारा आवश्यकता अनुभव की जाती है। विधानमण्डल उत्तरदायित्वविहीन दग से काय करने के कारण विगड जाते है। वस्तुत कायपालिका अपने नाम के अनुकूल नहीं रह जाती। वह अपने निणया को क्रिया वित करने म असफल रहती है। विधान मण्डल का नतिक पतन हो जाता है क्यांकि स्वतान होने के कारण उसके द्वारा ऐसे निणय निये जाते हैं जिनका फल स्वय उसे नहीं अपितु दूसरा को भोगना पडता है। राप्ट्रपति निश्चित समय के लिए निर्वाचित होता है। अपन पद से इस अविध म उसे हटाया नहीं जा सकता । सभी व्यवस्थाएँ निश्चित समय के लिए होती है । इसमें नमनीयता के तत्व का अमाव होता है, सभी कुछ कठोर, निश्चित एवं निधारित होता है।'

(4) राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय देश म वडी उथल पूरल होती है। क्यी कमी तो विद्रोह तक हो जाते हैं। यह दक्षिण अमेरिकी राज्यो, न कि संयुक्त राज्य अमे

रिका, के सम्बाध में अधिक सत्य है।

(5) अध्यक्षात्मक पद्धति में राष्ट्रपति के सचिवों को विधानमण्डल की काय वाही म भाग लेने की कोई सुविधा प्राप्त नहीं है, अस्तु विधानमण्डल एव प्रशासन में नोई जीवनदायी सम्पक नही होता । शासन की आवश्यकताओं को विधानमण्डल समभने मं असमय रहने के कारण शासन की मागा को उसके द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है। वह उनकी उपेक्षा एव अवहेलना भी कर सकता है।

³³ Willoughby The Governments of Modern States, pp 259 60 34

Bagehot The English Constitution, Ch 1, 1963, pp 69 81

18

विटिश संसदीय अथवा मन्त्रिमण्डलीय कार्यपालिका [BRITISH PARLIAMENTARY EXECUTIVE]

ससदीय कायपालिका का सबश्रेष्ठ उदाहरण ब्रिटिश मिनिमण्डल है। सी एक स्ट्राग के अनुसार, "शासन के क्षेत्र में इमलेण्ड की मित्रमण्डलीय कायपालिका का विकास संबाधिक शिक्षात्रद है।" ब्रिटिश ससदीय प्रणाली का विश्व के अनेक देशों जसे कनाडा बास्ट्रेलिया, मारत, युजीलैण्ड आदि ने अनुगमन किया है।

मित्रमण्डल इगलैण्ड की यथाय कायपालिका है। बायसी के अनुतार, "राज्य का हर काय सम्राट के नाम पर किया जाता है परन्तु इसलेण्ड के सासन की वास्त कि कायपालिका मित्रमण्डल है। "" यदापि विधिक होट्ट से प्रभुसता साम्राट एव ससद में अधिष्ठित है, लेकिन व्यवहार में मित्रमण्डल सखद एव सम्राट घोरो री सिका का उपमोग करता है। अित्रश्य स्वाय एव योजना तथा अवसर एव चुचि की सतान है। जिटिश मित्रमण्डल के सम्बंध में व्यक्त विधिन्न पिद्वारों है। मिन्न मत उसके महत्व को व्यक्त करते हैं। जिटिश मित्रमण्डल सर्वेल से अनुतार, "राज्य-मीतिक महराव का आधार स्तम्म है। विद्या मित्रमण्डल सर्वेल से प्रवार, "राज्य-मीतिक महराव का आधार स्तम्म है।" उसके स्मीर ने राज्य में पिदरा मित्रमण्डल सर्वेल एवं जहां का वालव चक है।" जीन मेरियट व अनुतार, "मित्रमण्डल सर्वे प्रवार सम्मण्य राजनीतिक य'त्र पस्कर मारता है।" विष्य पर प्रमर्भ

¹ Strong op est, 1963, p 237

² Dicey The Law of the Constitution, 1959, p 162

³ Cabinet m "the keystone of political arch "-Lowell; cited by Ogg and Zink Modern I oreign Governments, 1956, p. 86

⁴ Cabinet is 'the steering wheel of the ship of the State '-R missy Mur How Britain is Governed op cit, p 03

⁵ Cabinet is "the pivot round which the whole political machinery practically revolves" — John Murriott Inglish Political Institution 1955, p. 69

के अनुसार मित्रमण्डल शासन का के द्वीय निर्देशक यात्र है। ⁶ 19वी सदी के प्रसिद्ध ब्रिटिश विविशास्त्री बेजहोट के अनुसार, "मित्रमण्डल राज्य के विधायी भाग को काय पालिका अंग से जोडन वाला वकसुंबा है।''⁷ ग्लेडस्टोन के बनुसार, "मन्त्रिमण्डल सूप पिण्ड है जिसके चारो तरफ अय लघु नक्षत्र चक्कर काटते हैं।' व डायसी के जनुसार, "म**ि**तमण्डल इगलैण्ड की वास्तविक कायपालिका है यद्यपि सब काय राजा क नाम पर किया जाता है।" एक अय सादम म ग्लेडस्टोन न "मिनमण्डल की एक एसे त्रिमुसी यात्र से तुलना की है जो बिटिश सविधान को जियाबित करने के लिए राजा या रानी, लॉडसभा या काम स समा को एक सूत्र म वांघता है।"10

सिडनी लो के अनुसार, ''इगलैंण्ड के अभिसमयो के अनुसार मित्रमण्डल उत्तर दायी कायपालिका है जिसका प्रशासन पर पूण नियानण होता है एव जिसके सम्पूण काय व्यापार का निर्देशन किया जाता है लेकिन इस पर प्रतिनिधि सदन (कॉम स समा) जिसके प्रति यह अपने कार्यों एव मुला के लिए उत्तरदायी है, का कठोर नियात्रण होता है।"11

मि नमण्डल को ब्रिटिश सविधान का के द्रीय तत्व एव मुख्य लक्षण माना जाता है। यह ब्रिटिश शासन काएकमान महत्वपूण यन है। ब्रिटिश मित्रमण्डल को 1937 ई मे Ministers of the Crown Act के पारित होने तक कोई विकि मायता प्राप्त नही थी अर्थात् इसका आधार कोई ससदीय विधि नहीं थी । इसका विकास ऐतिहासिक परिस्थितिया एव सयोग का परिणाम है। यह परम्पराओं की देन है। यह जानवूक्कर निर्मित सस्या नही है। ब्रिटिश मिनमण्डल बहुमत दल के सस दीय प्रमुखो का स्थायी परत्त अनीपचारिक सगठन है।

⁶ Cabinetis "the central directing instrument of the Government" -L S Amery Thoughts on the Constitution, 1964 p 70

Cabinet is a 'combining hyphen which joins a buckle which fastens the legislative part of the state with the executive part -Walter Bagehot The English Constitution, 1963, p 68

Cabinet is "the solar orb round which other bodies revolve"

⁻Gladstone, cited by Ogg & Zink op at p 86

Dicey, A V cited by J A R Marriott op cit p 68

^{&#}x27;The cabinet in the threefold hinge that connects together for 10 action the British Constitution of King or Queen Lord and Commons "-Gladstone, cited by Marriott op cit, p 68

According to the conventions of the Constitution, the cabinet is 11 the responsible executive having the complete control of administration and general direction of all national business but under strict supervision of the representative chamber which II is accountable for all its acts and omissions -Sidney Low

मन्त्रिमण्डल का इतिहास एव विकास

ब्रिटन म मित्रमण्डल का विकास घीमी गति से हवा है और उसके प्रगति पथ का प्रत्यक नवीन कदम विसी न किसा विधिक कल्पना द्वारा आवत है। विधिक हृष्टि से मित्रमण्डल प्रीवी काउन्मल (Privy Council) की एक समिति है। प्रीवी कॉउन्सल नामन ग्रेट काउन्सल या बपूरिया (Curia) की वदा-परम्परा म है। नामन काल मे न्यूरिया राज्य के परामशदाताना एव प्रशासका का स्थायी निकाय था। यह समिति पापिक, वित्तीय, कायपालक एव परामदादायी क्तब्य सम्पादित करती थी। समय बीतन के माय क्यूरिया के न्यायिक कतव्या की दो न्यायालयो -- किंग्स बैच एव कॉमन्स त्यायालय—द्वारा सम्यादित किया जाने लगा एवं वित्तीय दायित्व कायागार द्वारा निभाये नान लग । सामान्य प्रशासन म राजा को परामश देन का काय परिषद द्वारा किया बाता रहा । हनरी सप्तम के काल म यह निकाय अत्यधिक लोकप्रिय हो गया था । एडवड पट्टम ने इस प्रीवी परिषद का नाम प्रदान किया। एडवड पट्टम ने ही प्रीवी परिपद की एक समिति (Committee of State) को महत्वपूग कार्यों को सम्मादित करन का भार सौंपा था। ट्यूडर-काल भ प्रीवी परिपद समितियो मे विमाजित कर दी गयी थी। विभिन्न राजाओं के काल में इसकी सदस्य-संख्या में अन्तर होता रहा। 1509 ई में इसकी सदस्य-सस्या 19 और 1547 ई में 25 थी। मेरी के शासन-नाल म इसकी सदस्य-सख्या 46 थी और एलिजावेय के शासन काल मे इसमे कुल 13 सदस्य थे ।

बेकन (Becon) ने सवप्रथम केविनट (cabinet) खब्द का प्रयोग किया है। इसके पश्चात क्लेरलंडन (Clarendon) ने 1640 ई में केविनेट शब्द का प्रयोग एक ऐसी सस्या के लिए किया जिसम प्रीवी काउन्सन के राजा के विश्वासपान सदस्य सामित्र हाते थे और प्रधासन में उसकी सहायता करते थे। उस समय जनता में इनके प्रति तन्देह था। इनका कोई विधिक आधार न होने के नारण वह सत्त के प्रति जनत्वायों नहीं ठहराया जा सकता था। उस समय सबद सर्वाच्य एवं सम्प्रभु सस्या नहीं औ। इस प्रकार केविनेट प्रोवी परिषद का एक प्राग मात्र बनी रही। इस समय तक दलीय व्यवस्या का भी पुण विकास नहीं हुआ था।

मकांते न प्रीवी परिषद की इस लघु समिति के लिए आ तरिक परिषद (Interior Council) झब्द का प्रयोग किया है। इसके अधिवेदान समा भवन में न होकर एक कमरे (cabinet) में होते थे। चाल्स प्रथम के शासन काल में भी कैबिनेट की यही स्थिति थी। 12

चात्स प्रथम के झासन-काल म इगलण्ड के सबैघानिक इतिहास के इस मह

¹² Strong op est p 238

पूण प्रक्त का निणय हुआ था कि नाउन एव ससद की सत्ता नया है ? हमरणीय है, नाउन निरकुश नहीं हो सकता। चात्स प्रथम के शासन काल में (1642 ई) यह महत स्वय प्रारम्म हुआ था। 1643 ई के व्यापक प्रदश्न (Grand Remonstrace) में राजा से यह प्राथना की गयी थी कि वह अपने सताहकारों के रूप म सबद के विक्वासपान व्यक्तिया को ही नियुक्त करे। स्पट है कि इस समय म सबद के प्रति मिन्यों के उत्तर दायित्व का प्रक्त निहित था। ससद इस सयय म निवयी हुई थी। 1648 ई म चात्स प्रथम की फासी दे दो गयी। मिन्या को सदद के प्रति उत्तर वायि वनाने की प्रक्रिया का स्टाय के अनुसार यह प्रथम चरण था।

चाल्स द्वितीय के शासन-काल म प्रीची काउ सल के सदस्यों की सख्या म वृद्धि हुई थी। चाल्स द्वितीय ने बृहद प्रीची परिषद के सदस्या के स्थान पर 1667 ई में चुने हुए कुछेल सदस्यों की एक अनीपचारिक समिति स परामदा करता प्रारम्भ कर दिया था। इसे 'कवाल' (CABAL) मी कहा जाता था। इस शब्द की रचना राजा के हारा नियुक्त पांच परामदाशाताओं के नामों के प्रथम अक्षर को लेकर की गयी थी। इर परामदाशाताओं के नाम थे—विकास (Clifford), एशले (Ashley), विकास (Buckingham), एसलिंग्टन (Ashlegton) तथा लो डरडोल (Londordole)। यह विकास लोकप्रिय नही था और न सबत के प्रति उत्तरदायी ही था। यह सभी परामवाता केवत राजा के कुरापान थे। लेकिन इसी 'कवाल' य परवर्ती मिनमण्डलीय व्यवस्था के बीज देखे जा सकते है। राजा के कुछ प्रमुख परामवादाता) का यह लच्च वस्तु उद्देश देखे सासन वाय में सामृद्धिक रूप से एयमश्र देता था।

मित्रमण्डलीय उत्तरवायित्व के विद्वा त की नीव चाल्ख द्वितीय के काल म ही
निश्चित रूप से पड चुकी थी। 1643 ई मे राजा से ससद के विश्वासपात्र मित्रमें की नियुक्त करने की प्राथना की गयी थी। बिक्यम (Buckingham) एवम् वेदव्य (Wentworth) पर ससद द्वारा चाल्य प्रथम के काल मे महानियोग लगाये गर थे। 1679 ई म डेनवी (Denby) पर महानियोग लगाकर मित्रमण्डलीय उत्तर वायित्व की पूणरूपेण स्थापना की गयी थी। लेकिन सामृहिक उत्तरदायित्व के सिद्धात का विकास 17वी सदी मे नहीं हो सका। स्टूबद्यवधी अतिम दो शासका के काल मे दलीय प्रणाली के विकास ने यतमान मित्रमण्डलीय व्यवस्था के विकास म योग दिया है। 1688 ई तक मित्रमण्डल का निर्माण कोमन्स म बहुमत दल के सदस्या में से होना प्रारम्भ नहीं हुआ था लेकिन रक्कहीन काति (1688 ई) तक मित्रमण्डल सावी प्रपाली के पश्चल हो चुका था और राजा के प्रति उत्तरदायी होते हुए भी वह ससद को मा यता देने लगा था।

रक्तहोन फ्रान्ति (1688 ई) के पश्चात मि प्रमण्डलीय व्यवस्था

विलियम तृतीय एवं रानी ऐनी के काल में मित्रमण्डल सर्वोच्च परामशदायी परिपद एवं राज्य की कायपालिका के रूप में मा यता प्राप्त कर चुका था। विलियम तृतीय ने सत्तारूढ होने के परचात दोना दला (टोरी एव ह्विम) में से अपने मित्रयों का चुनाव किया था, लेकिन इससे परिषद की एकता नष्ट हो यथी। सदस्यगण सहयोग-पूदक काय न कर सके। अत 1695 ई म ह्विम दल के नेता सुङरतण्ड ने राजा को कामन्त के बहुमत दल—ह्विम दल—म से ही मित्रयों का चयन करने हेतु तैयार कर लिया। इस समय राजा हो मित्रमण्डल के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता था। इस ह्विमदाय मित्रमण्डल को ह्विम जुटां (Whug Junta) की सना दी गयी। यह पित्रमण्डल तीन वय तक सत्ता व्हा पा। यह एक एव बहुमत दल का मित्रमण्डल या। यह एक एव बहुमत दल का मित्रमण्डल या।

विलियम तृतीय के परवात राजी ऐनी सिंहासनास्ट हुई थी। इसके कायकाल में 1701 ई में सेटलमें ट एक्ट (The Act of Settlement) की धारा 3 के द्वारा मिनाएक्ल के विकास को प्रीवी परिषद की धार्तियों को पुनर्जीवित करके अवरुद करन जा जानदूसकर प्रयत्न किया गया था। वेकिन उक्त धारा एक मृतपत्र बनी रिंग । ऐनी नि विलयम की माति ही मिन्त्रयों को मनोनीत करती एव मिनाएक्ल की अध्यक्षता करती थी। 1708 ई से 1710 ई तक ह्विग दल एव 1710 ई से 1714 ई तक टोरी दल के मिनाएक्ल थे। इन दोनी दलों का इस काल में ससद म बहुमत था। ऐनी के शासनकाल में एक दिशा में अवस्थ महत्वपूण विकास हुआ या। एनी टोरी दल की समयक थी लेकिन उसने अनिक्छापूत्रक कमिन समा मं यहुमत रखने वाले ह्विगदसीय मीनमण्डल को स्वीकार किया। स्पष्ट है कि इसरे मिनाएक्ल से खबदस्या के इस सिद्धात को स्थापना हुई कि रावा केन चाहते हुए मी मिन्न पण्डल ससद के विश्वासपन्त पदास्ट बना रहेगा। ऐनी के समय तक प्रधानमाभी ने पद की मृदिन नहीं हुई थी। यह काय हुनीवर वधीय शासको के साय्य मं या।

हनोवर-बरा एव मित्रमण्डलीय व्यवस्था

प्रथम हनोबर बशीय सासक आँज प्रथम के सिहासनारूढ होने के परपात मित्रमण्डल के सगठन एवं कायपढित म महत्वपूष परिवतन का सूत्रपात हुआ। इस समय सक मित्रमण्डलों की अध्यक्षता राजा करता था। बाज प्रथम एवं द्वितीय थेगे। ही जमन वे। उह अधेजी आधा का ज्ञान नहीं था और न वे उपलेख्ड भी राजािति में राजािति में कि एवं है पे पी से पी से से से साम प्रथम प्रथम एवं सित्र से पी से से स्वाप्त प्रधानमंत्री से से सा अर्थात् प्रधान में निर्मा से से स्वाप्त प्रधानमंत्री से से सा अर्थात् प्रधान में मित्रमण्डल की अध्यक्षता करने लगा। इस परिवतन में निम्न यो परिणाम हुए

(1) मीं त्रयों को अधिक स्वतंत्रता से मामसा पर विचार करों वा अससर प्राप्त हुआ और वे निश्चित योजना एवं नीति राजा ने समक्ष उपस्थित नरों एवं।

(2) मित्रमा ने राजा की अनुपस्थिति म अपो भ से ही एक मश्ती को स्मान सता हेतु चुनना प्रारम्म कर दिया। यह प्रमुख तेता हुआ परता था और बार में नही प्रधानमंत्री कहा जाने सत्या।

सर रॉवट वालपोल (Sir Robert Walpole) वह प्रथम मन्त्री भा विमान !

प्रथम प्रधानमंत्री होने का सीमाग्य प्राप्त हुआ। वालपोल को मित्रमण्डलीय व्यवस्था की आधारशिला रखने का श्रेय प्राप्त है। उसने मुख्यमंत्री के रूप मं अपने सहगीविषा से पूण मिक्त की अपेक्षा की तथा ससद म सामूहिक रूप से आवरण करने पर वत दिया। 1730 ई में वालपोल ने टाउनसेण्ड (Townsend) को पदत्याग करने के लिए मजबूर किया था क्योंकि वह उसकी नीतियों से असहमत था। इसी प्रकार 1733 ई में एक्साइज विधेयक का विरोध करने के कारण चेस्टरफील्ड (Chester field) को त्यापपन वेना पड़ा था। वालपोल ही कोपागार का प्रथम लाड (First Lord of Treasury) एवं विस्तमान्त्री (Chancellor of Exchequer) था। उपने प्रधासन सन्द धी नीतियों को नियाचित्र एवं निर्मारित किया तथा सामूहिक उत्तरदायित के सिद्धान को लाग किया।

1742 ई म वालपोल ने कॉम स म पराजित हो जाने के कारण अपने पद से स्यागपन दे दिया था यद्यपि उसे राजा का विश्वास प्राप्त या। उसके स्यागपन के साथ सम्पूण मिनमण्डल ने भी स्यागपन दे दिया। इस प्रकार सामूहिक उत्तरदायित के सिद्धान की स्थापना हुई।

क अस्तात का स्थापना हुइ।

जॉज ततीय (1760 1820) ने शाही सम्मान एव सत्ता को पुन स्थापित

न रते का प्रयत्न किया था। उसका यह प्रयत्न घडी को उन्टा चलाने का प्रयत्न मा

या। जॉज ततीय द्वारा सत्ता को हस्तगत करने के इस प्रयत्न ने मिनमण्डल में राजनीतिक

एकता एव उत्तरदायित्व के गुणों को अधिक हव किया। अमेरिकी उपनिवेश को खोने के

पश्चात राजा की व्यक्तिगत सरकार का ज तहो यया था। टोरी दल मी मिनमण्डली

ग्यवस्था के प्रति ह्वित दल की माति ही आस्थावान हो याग था। 1782 ई में ताइ

रोविनमम (Lord Rockingham) का मिनमण्डल एक हो राजनीतिक दल वे

निर्मित प्रयत्म मिनमण्डल था। कितन्द पिट (Pitt, the Younger) ने मिनमण्डलीय

व्यवस्था को और अधिक पूणता प्रदान की थी। उसने मिनमण्डल में से राजा के

राजमहल के अधिकारियों जैसे लॉड चेन्यर्लण्ड एव अस्वपति (Master of Horse)

को मिनमण्डल वे हटा दिया। प्रारम्भिक हिचकिचाहट के पस्पात राजी विवटोरिया ने

मिनमण्डलीय व्यवस्था को पूणक्षेण स्वीकार कर तिया था एव सर्वैधानिक गासक

की प्रमान का पूर्ण सम्मादन किया था।

मन्त्रमण्डलीय व्यवस्था की विशेषताएँ

मित्रमण्डल के उपरोक्त इतिहास एव विवरण से यह स्पष्ट है कि मित्रमण्डल की अपनी कुछ मुख्य विद्येषताएँ हैं। मेरियट के अनुसार वे निम्नत हैं

- राजा मित्रमण्डल का अग नही होता।
 - (2) ब्यवस्थापिका एव नायपालिका म पनिष्ट सम्बाध हाता है।

(3) राजनीतिक एकरसता अर्थात् मित्रमण्डल वे सदस्य एव हा राजनीतिक विचारधारा के होते हैं। (4) सामूहिक उत्तरदायित्व ।

(5) प्रधानम त्री की प्रमुखता अर्थात अय म त्री उसके अधीन होते है।¹³

प्रो ऑग के अनुसार 18वी सदी के अत तक मिनमण्डलीय व्यवस्था की निम्न विशेषताएँ मली प्रकार स्थापित हो चुकी थी

(1) मि त्रमण्डल के सदस्यों को ससद का सदस्य होना चाहिए।

(2) सभी मित्रियो को एक ही राजनीतिक दल एव राजनीतिक विचारो का होना चाहिए।

(3) मित्रया को सदन का विश्वास प्राप्त होना चाहिए अर्थात उन्हें बहुमत दल में से चना जाना चाहिए ।

(4) मित्रयो की एक ही स्वीकृत नीति होनी चाहिए।

(5) सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धात अर्थात मन्त्रियण्डल को कॉम स समा कंप्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायो होना चाहिए।

(6) मुख्यम त्री की अधीनता।

एचं की ट्रेल (H D Traill) ने मिनमण्डल की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है

इसके सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होने चाहिए ।

(2) इनके एक से राजनीतिक विचार होने चाहिए और ये कॉम स समा म बहुमस दल म से निर्वाचित होने चाहिए।

(3) सभी सदस्या को एक सी नीति का अनुगमन करना चाहिए।

(4) सामाय उत्तरदायिस्य के अधीन कार्य करते हा अर्थात् ससद द्वारा निंदा का प्रस्ताव पारित होने पर सभी सदस्यों को सामूहिक रूप से स्थागपन दे देना चाहिए।

(5) एक मुख्यमात्री की अधीनता को स्वीकार करते हा 114

उपरोक्त विद्यवताओं के अतिरिक्त एक और विश्वेषता है और वह है गोपनीयता (secrecy)। मिनिमण्डल के सभी काय गुप्त होते है। मिन्नया को अपने मतभेष प्रकट नहीं करने चाहिए। इसस यित्रमण्डल की एकता नष्ट हा जाने मय रहता है।

स्ट्राग ने मित्रमण्डल की उपरोक्त विशेषताओं को तीन सब्दा म ब्यक्त किया है—एकरसता (homogenetty), एकता (solidarity), एव एक नेता की अधीनता (Common loyalty to a Chief) i

मन्त्रिमण्डल एव मन्त्रि-परिषद

मित्रमण्डल (cabinet) एव मित्र-परिषद (ministry) के अन्तर को समस्ता

Marriott English Political Institutions, 1938, pp 78 84
 Quoted by Strong op cit, pp 239-240

आवदयक है । मित्र-परिषद एक वहद निकाय है । यदि मित्र-परिषद का हम वहा वृत्त मान लेत हैं तो मित्रमण्डल उसके मीतर लघु वृत्त है। मित्र-परिषद के अन्तगत नाउन के वे सब उच्च अधिकारी आ जाते हैं जो अपने कार्यों एव नीतिया क ^{लिए} कॉम स समा के प्रति उत्तरदायी होते हैं एवं जो बहुमत दल के सदस्य हाते हैं। इसके विपरीत, मिनमण्डल के अत्तगत केवल प्रमुख विमागा के मात्री हाते हैं। प्रधान मात्री इ ही प्रमुख सदस्या स एक निकाय के रूप म समय समय पर इनके अधिवेशन बुता कर देश के प्रशासन के सम्बाध म परामश करता है। मित्र-परिपद की सदस्य-सस्बा निश्चित नहीं है। वह सामा यत 60 या 70 होती है। द्वितीय विश्वयुद्ध काल में ती इसकी सदस्य-सख्या 100 तक पहुँच गयी थी। मित्र परिपद म सनी प्रकार के मंत्री होते हैं। ग्रेट ब्रिटेन मे मित्रयों की चार प्रमुख थेणियाँ होती हैं—(1) विमागाध्यक्ष ---जैसे विदेश मंत्री, सुरक्षा मंत्री एव वित्तमंत्री, आदि । (2) व मंत्री जो विभाग घ्यक्ष नही होते- जैसे लॉड प्रीवी सील (Lord Privy Seal), लॉड चान्सलर (Lord Chancellor)—यह उच्च पदाधिकारी होते हुए भी विमागाध्यक्ष नहीं हातं हैं। (3) ससदीय जपसचिव (Paliamentary Under Secretary)। (4) राजमहन के अधिकारी (Officers of the Household)—जैसे खजाची एव उपन्येम्बरनन। इन चारो वर्गों के अधिकारियों को संयुक्त रूप से मित्र परिषद कहते हैं। सामायत प्रथम दो प्रकार के मानी तथा कुछ अय प्रकार के सदस्य मिनमण्डल के सदस्य होते हैं। मिनमण्डल के सदस्या की सक्या निश्चित नहीं है। यह सरया सामा यत 20 स 25 तक होती है। प्रारम्म म केवल 7 या 8 सदस्य ही मि त्रमण्डल म होते थे। 19वी सदी म इनकी सदस्य सख्या 13 14 तक थी। प्रथम विश्व-गुद्ध के काल म सदस्य सल्या बढकर 20 तक हो गयी थी।

मिनमण्डल के द्वारा जो नीति निर्धारित की जाती है वही मिनिश्वित द्वारा नियाबित की जाती है। मिनिश्वित की माति परिषद के निर्वार्त अधिवेदान नहीं होते। प्रत्येक मनी केविनेट का सदस्य नहीं होता है अधितु हर केवि नेट मनी मिनिश्वित का सदस्य होता है। मिनिश्वित है केविन नेट मनी मिनिश्वित का सदस्य होता है। मिनिश्वित है केविन व्यक्ति का कोवित्य के निर्वार होते है लेकिन मिनिश्वित है। मिनिश्वित है। है लेकिन मिनिश्वित की कोवित्य के सिद्ध कार्यों के निर्वार निर्वार के कोवित्य को निर्वार केवित है। मिनिश्वित है। मिनिश्वित केवित स्वत्य अपने दल के प्रमुख नेता होते है। वे दल एव सरकार के कायकम एव नीति पर विचार विमय करते हैं। मिनिश्वित है। मेनिश्वित होते है। यह सामित कर प्रमुख नेता होते है। वे दल एव सरकार के कायकम एव नीति पर विचार विमय करते हैं। मिनिश्वित को प्रयोग करते हैं। मिनिश्वित होते है। यह सामित की सत्ता का यमाथ स्व पे प्रयोग करते हैं। मिनिश्वित निर्वाता एव राज्य वा चालक यम है।

इसके अविरिक्त आ तरिक मिंत्रमण्डल नामक एक नवीन सस्या का विकास हुआ है। सम्पूण मिंत्रमण्डलीय व्यवस्था की मीति यह मी विकास का ही परिणाम है। प्रधानमंत्री के लिए 20 25 व्यक्तिया के साथ सासन के सम्य प म विचार-विमास करना व्यावहारिक इंग्टिंग साथ सम्यव नहीं होता है अब प्रधानमंत्री अपने विस्तत, प्रमुख तथा सहयोगी मिंत्रमा से मिंत्रमण्डल की बैठक के पूर्व अनीपचारिक चार तिया करता है जिससे मिंत्रमण्डल को बैठक के पूर्व अनीपचारिक चार तिया करता है जिससे मिंत्रमण्डल को बैठक के पूर्व अनीपचारिक चार तिया करता है जिससे मिंत्रमण्डल के बार वह अपनी नीति को सरता पूर्वक स्थोद्धत करता सके। मिंत्रमण्डल के बारिष्ठ एवं प्रमाववाली तथा सिक्स सदस्यों के इस अनीपचारिक निवास को आत्वरिक मिंत्रमण्डल कहते है। सर सिडनी सो ने नित्म संद्रमा मान्तरिक मिंत्रमण्डल की प्रकृति पर प्रकाश डाला है आतरिक मिंत्रमण्डल से तास्य्य ऐसे मिंत्रमण्डल की प्रकृति पर प्रकाश डाला है आतरिक मिंत्रमण्डल से तास्य्य ऐसे मिंत्रमण्डल से हैं "जो निर्देश तो देता है पर दु प्रशासन नहीं करता। इसके द्वारा सामूहिक उत्तरदायित्व को व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में पर्वत कर दिया गया है। इसका काम समा समा से सम सम सम होता है। कुछ कामों क बार में ते वह कामों स समा से पूण स्वत न होता है। यह हमारी दलीय व्यवस्था के बाहर है तथा गुग्त होत हुए भी गुन्त अधिवेशन के अर्थों म पूणस्रेण गोपनीय नहीं है।"

ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के कार्य

मिन्नपण्डल अनेक प्रकार के कतव्यों का पासन करता है। व्यापक शक्तियों के कारण उसकी तीन्न आलोचना की गयी है। मिन्नपण्डल के कार्यों एव शक्तियों का आघार विधिक्त न होकर परम्परागत है। सिद्धात रूप मिन्नपण्डल एक ऐसी परामधादायी समिति की मौति है जिसका काय काउन की शासन कार्य में परामधादायी समिति की मौति है जिसका काय काउन को शासन कारण मिटिया मिन्नपण्डल व्यवहार में देश की यथाथ कायपालिका बन गयी है। शासनत न समिति के मण्डल व्यवहार में देश की यथाथ कायपालिका बन गयी है। शासनत न समिति के मिन्निलिखित है

(1) ससद के समक्ष प्रस्तावित नीति का अतिम रूप से निर्घारण करना।

(2) ससद द्वारा निधारित नीति के अनुसार राज्य की कायपालिका पर सर्वोच्च नियात्रण रखना ।

(3) राज्य के विभिन्न विभागा के अधिकारों का सीमाकन एवं जनमं निरन्तर समावय की ध्यवस्था करता ।

उपरोक्त कार्यों के सक्षिप्त रूप म नीति निर्धारण, कायपालक एवं सम वया-एमक श्रेणी म वर्गीकृत कर सकते हैं। ससद का काय शासकीय नीति पर अतिम स्वीकृति देना होता है। तृतीय काय कार्यपालक काय का एक अय है। अत उपरोक्त प्रिपोट ने मिन्नमण्डल के ब्यवस्थापिका एवं कायपालिका सम्बंधी केवल दो ही मुख्य काय माने हं। इसके अतिरिक्त मित्रमण्डल का व्यापक वित्तीय अधिकार भी प्राप्त है। अत अध्ययन की दृष्टि से मित्रमण्डल के कार्यों को व्यवस्थापिका, काय पालिका एव वित्तीय श्रेणियों में वर्गीकृत करना श्रेयस्कर होगा।

स्यवस्थापिका सम्बाधी काथ—ससद के अधिवेशन आहूत करने, सनावसन करने एव उसके विघटन की शक्तियाँ मिन्नमण्डल में निहित हैं। ससद का कायक्रम मिन्न मण्डल द्वारा ही तैयार किया जाता है। मिन्नमण्डल का एक प्रकार से ससद क समय पर एकाधिकार होता है। समस्त शासकीय विधेयक मिन्नमण्डल द्वारा ही प्रसुक्त किये जाते हैं। कीन से विधेयक ससद में प्रसुक्त किये जाते हैं। यह निणय करना भी उसी का काय है। ससद में अपने द्वारा प्रसुक्त विधेयकों को पारित कराना में उसी का बायद्व होता है। मिन्नमण्डल नीति का निर्धारण करता है एव आवश्यक मामना पर इसके द्वारा विचार निम्न किया जाता है। नीति-निर्धारण के बाद उसके किया वियार तैसु आवश्यक विधि निर्माण काय मिन्नमण्डल का हो काय है। जब तक मिन्न मण्डल को बहुमत का समयन प्राप्त है, मिन्नमण्डल ससद सं सहज ही स्वीकृति प्राप्त

के जित्र में क्यापक शक्तिया प्राप्त हो गयी है।

कायपालिका सम्बन्धी काय—मित्रमण्डल देश की सर्वोच्च कायपालिका है। देश
की विदेश नीति, आ तरिक व्यवस्था एव शातिक लिए आवश्यक नीतियों एव कायक मित्रमण्डल हारा हो निर्धारित किये जाते हैं। युद्ध एव शाति के प्रश्तो का यही तम करती
है। विदेशों से इसी के द्वारा सि ब-वार्त की जाती है। नीतिया को स्वीकृत करना
एवं सस्वीय विधियों को नियावित करना ससद का हो दायित्व है। विमिन्न विभागों
पर नियात्व रखना एवं जनम सम वय स्थापित करना मित्रमण्डल का प्रमुख दायित्व
है। हेल्डेन समिति ने इस सुद्ध में व्यापक सिकारिकों की थी।

कर लेता है। सच तो यह है कि ससद यित्रमण्डल की अनुमति एव परामश छे हैं। विधि निर्माण करती है। प्रदत्त व्यवस्थापन के फलस्वरूप यित्रमण्डल को विधि निर्माण

पर नियानण रखना एव जनम सम वय स्थापित करना मिनमण्डल का प्रमुख दायित है। हेल्डेन सिमित ने इस स दम ये ब्यापक सिकारिक्षे की थी। इस सिमित ने इस स दम ये ब्यापक सिकारिक्षे की थी। इस सिमित ने शासकीय कार्यों के सम्पादन हेतु निम्न मुख्य निमागों की स्थापना का सुमाव दिया था (1) बित्त, (2) सुरक्षा, (3) बिदेश विमाग, (4) शोष एवं पूचना, (5) उत्पादन (कृषि, न एवं महस्ती, उद्योग सिहत), (6) यातायात एवं वाणिज्य, (7) रोजगार को व्यवस्था (Employment), (8) शिक्षा, (9) स्वास्थ, (10) याय, एवं (11) पूर्ति (Supples)। सिमिति का यह भी सुभाव था कि मिन मण्डल के अधिवेदन श्रीम होते रहने चाहिए। व्यक्तिमत रूप से उन मित्रयों से परमर्थ किया जाना चाहिए जिनक कार्यों पर निर्मारित नीति का प्रमाव पढ सकता हो एवं उद्ये ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसक स्वर्धों नीतियों को विभिन्न विमागा द्वारा प्रमायशाली उत्य से नियानित किया जा सके।

इसके अतिरिक्त त्रिटिश मित्रमण्डल को नियुक्ति सम्बन्धी व्यापक धारियों प्राप्त हैं। राजदूता, साझाज्य क उच्च अधिकारिया जस यवनर जनरल, उपनिवसीय गवनरा आदि की नियुक्ति पर मित्रमण्डल ही विचार करता है। व्यवहार में ससद को इस सम्बच भ में हस्तक्षेप की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। लाड ऑक्सफोड तथा एस्विवयं का मत है कि निम्न विषयों पर मित्रमण्डल में विचार विमश्च नहीं होता (1) राजा के समादान के विशेषाधिकार के प्रयोग, (2) मित्रया का चयन, तथा (3) उज्बस्तरीय नियुक्तिया।

मिनमण्डल कायपालिका के रूप मे व्यापक शक्तिया का उपभोग करता है।

विस सम्ब घी काय—देश का वापिक वजट या वापिक आय व्यय का विवरण मिनमण्डल द्वारा ही तैयार किया जाता है एव ससद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ससद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ससद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ससद के समक्ष प्रस्तुत करने के 4 5 दिन पूर्व मिनमण्डल उस पर विचार करता है। ससद में बजट प्रस्तुत करने के 4 5 दिन पूर्व मिनमण्डल उस पर विचार करता है। ससद में बजट प्रस्तुत किय जाने के परवात उसम परिवतन या आधूलचूल सक्षीधन की मान ससद के सदस्यगणों को करने का अधिकार है। वजट की आते विचार ने का आधिकार वापित होता है। मिनमण्डल द्वारा ही सचित निधि (Consolidated Fund) प्रव आकरिमक निधि (Contingency Fund) सम्ब घी व्ययों का निर्धारण किया जाता है। राष्ट्रीय न्द्रण की व्यवस्या करना भी मिनमण्डल का ही काय है। मिनमण्डल द्वारा ही बजट में नवीन करा भी मिनमण्डल का ही वापित देश के वित्त का वापित्व अतिम क्या की प्रस्तावित किया जाता है। यद्यपि देश के वित्त का वापित्व अतिम क्या की सम्ब का होता है परन्तु मिनमण्डल ही यह निरिचत करता है कि राज्य जाय एव कीनसा नवीन कर लगाया जाय तथा किस सब में कितन व्यय किया जाय एव कीनसा नवीन कर लगाया जाय तथा किस सब में कितन व्यय किया जाय एव कीनसा नवीन कर लगाया जाय तथा किस सब में कितन व्यय किया जाय एव कीनसा नवीन कर लगाया जाय तथा किस सब में कितन व्यय किया जाय एव कीनसा नवीन कर लगाया जाय तथा किस सब में कितन व्यय किया जाय एव कीनसा नवीन कर लगाया जाय तथा किस सब में कितन व्यय किया जाय एव कीनसा नवीन कर लगाया जाय तथा किस सब में कितन व्यय किया जाय एव कीनसा नवीन कर लगाया जाय तथा किस सब में कितन व्यवस्त किया जाय एव कीनसा नवीन कर लगाया जाय तथा किस सब में कितन व्यवस्त किस प्रकार वसूत किया जाया एव कीनसा नवीन कर लगाया जाय तथा किस सब सब कितन वस्त किस सब सब सिंग किस सब सब सिंग किस सब सिंग किस सब सब सिंग किस सब सिंग किस सब सब सिंग किस सब सिंग किस सिंग किस सब सिंग किस सब सिंग किस सिंग

पाय सम्ब भी काय—लॉड चा सलर के परामश से काउन द्वारा महस्वपूण पायालयो के पायाधीशा की नियुक्ति की जाती है। काउन का क्षमा प्रदान करन, दण्ड को कम या स्थिगत करने का अधिकार है। परन्तु वह अपनी इन शक्तियो का प्रयोग गहमानी के परामश से ही करता है।

प्रस्थितपहल का संगठन

नवीन निर्वाचन या प्रधानमंत्री के त्यागपत्र के प्रधात ब्रिटिश राजा द्वारा काँमस सभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है एव उसके परामध से अप मत्रियों की नियुक्ति की जाती है। सन 1923 ई तक रीना सदनों में किसी भी सदन के सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता था। 19वीं सदी में अनेक प्रधानमंत्री लॉडस्या से ही चून पये थे, यथा लाड पामस्त्र, सॉड सिलस्वरी आदि । 1912 ई में लॉड सेलिस्वरी के त्यागपत्र क प्रचात कोई भी पीयर प्रधानमंत्री नियुक्त कही किया गया। 1923 ई म श्री बोनार ला (Bonar Law) द्वारा त्यागपत्र देने एर राजा ने लॉड कजन (साइसमा मं अनुदार दल के नता)

के स्थान पर वाल्डिवन (Baldwin) (कॉम स समा के सदस्य एव अनुदार दत के नता) को प्रधानमंत्री के लिए चुना था। राजा का यह मत था कि विरोधी दल अवात श्रम दल को लाइसमा मं चूकि कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है अत प्रधानमंत्री में कॉम स म से ही चुना जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री को कॉम स सना को ही सदस्य होना चाहिए क्योंकि मित्रमण्डल कॉम स समा के प्रति ही उत्तरदान होता है। इसलिए काम स मं प्रधानमंत्री का चयन लोकत त्रीय धारणा के अधिक अनुकूर है। बाद में लाइसमा की सदस्यता स्वीकार करने पर स्वय बाल्डिवन मं प्रधानमंत्री रहना स्वीकार नहीं किया था। अत अब ब्रिटेन मं यह सुनिविचत परम्परा या अनि समय है कि प्रधानमंत्री को कॉम स समा का ही सदस्य होना चाहिए।

प्रधानमानी मनिमण्डल के अनु सदस्या का चुनाव करते समय विमिन हीय कोणा से प्रमावित होता है। सिद्धात में मनिषयों के चयन के सम्बाध में उस पर कोई वधानिक निय नण नहीं होता परन्तु व्यवहार में कई प्रतिबंध होते हैं। मनिमण्डल में विभिन्न वर्गा, हितो एवं क्षेत्रा को प्रतिनिधित्व दिया जाना आवश्यक होता है। प्रधानमानी क्षेत्रीय, दलीय, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत हितो एवं क्षेत्रा नहीं कर सकता। दल के महत्वपूण एवं प्रमाव हाली सदस्यों को उसे मिनमण्डल में स्वापित करते से स्वाप्त देता है। बक्तिशाली दनीय सदस्यों को दक्ष में मामिल करने सं मिनमण्डल अधिक द्यक्तिशाली हो जाता है। उत्त स्वाप्त को स्वाप्त के स्वाप्त

मन्त्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व

मिनमण्डल निरकुश रूप से अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। अपने कार्यों के लिए वही उत्तरदायी होता है। मिनमण्डल का उत्तरदायित्व मिसूनी हैं। मिनमण्डल या उत्तरदायित्व का कोई विधिक आधार नहीं है, यह प्रया अभिसमय पर आधारित है। मिनमण्डल प्रकारा तर से तीन अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी होता है—(1) सम्राट के प्रति, (2) कॉम स के प्रति, एव (3) देश के मतदाताओं के प्रति। सम्राट के प्रति उत्तर (3) देश के मतदाताओं के प्रति। सम्राट के प्रति उत्तर (3) देश के मतदाताओं के प्रति। सम्राट के प्रति उत्तरदायां से ति उत्तर प्रति।

प्राचीन काल म म नी केवल राजा या सम्राट के प्रति ही उत्तरदावी होते थे। वे राजा के द्वारा निमुक्त किये जात थे एव उसी के प्रसाद-प्रयत्त पदारूढ रहते थे। प्रजात न के विकास के साथ राजा को बक्ति मिनम्ब्यल को हस्ता तरित हो गयी है। प्रजात न के विकास के साथ राजा को बक्ति मिनम्ब्यल को हस्ता तरित हो गयी है। राजा वस मिन्यों के परामर्थानुसार काय करता है। सम्राट के प्रति उत्तरदायित का अथ यह है कि विधिक हिन्द से राजा के प्रसाद पही । सम्राट स्वाचिक व्यवस्था है। व्यवहार में सम्राट सर्थानिक अध्यक्ष है। के स्वाच के स्वाच के स्वाच त्या स्वाच स्वाच से सम्राट सर्थानिक अध्यक्ष है। उत्तर साथा के प्रति मिन्यों का उत्तरदायित कोई गम्भीर बात नहीं है। इसका अभिग्राय तो केवल यह है कि मित्र

मण्डल सम्राट को प्रत्येक बात की सूचना देता रहे जिससे कि शासनीय कागजात देख कर राजा को परामश देने वा जबसर प्राप्त हो सके। वेजहोट क जनुसार यह राजा का अधिकार है कि उससे परामश क्या जाय। इसके अतिरिक्त उसे प्रोत्साहन एव चेतावनी देने का भी अधिकार प्राप्त है।

कॉमन्स के प्रति उत्तरदायित्व

यही वास्तिविक उत्तरदायित्व है। 1911 ई तक ब्रिटिश मिनमण्डल ससद के दोना सदना के प्रति समान रूप से उत्तरदायी होता था। पर तु ससदीय अधिनियम 1911 ई के पारित होने के फलस्वरूप लॉडसमा की श्रतिस्या कम हो गयी हैं और मिनमण्डल नेवल कॉम स समा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। इसका लप है कि मिनमण्डल तभी तक पदारूव रह सकता है अब तक कि उसे कॉम स समा का विद्वास अर्थात कॉम स समा के विद्वास अर्थात कॉम स समा के विद्वास अर्थात कॉम स समा के विद्वास अर्थात कॉम स समा को विद्वास अर्थात कॉम स समा को विद्वास अर्थात कॉम स समा को कि स में के वित्तन को कम करने का प्रस्ताव या कोई एसा गैर सरकारी प्रस्ताव जिसका कि मिनमण्डल विरोध करता हो, की स्वीकृति को यिनमण्डल के प्रति विद्वास सामा जाता है।

काम स समा के प्रति मित्रमण्डल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। आधुनिक राजनीतिक जाचरण को यह जिटन का महत्वपूण अनुदेय है। हर मान्नी काम स के प्रति व्यक्तिगत एव सामूहिक रूप स उत्तरदायी होता है। जो मानी जिस विमान स सम्बिपत होता है वह उसके कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। के उत्तरदायी होता है। के उत्तरदायी होता है। के अने माने अपने विमान के कार्यों के लिए वह कह कर नहीं वच सकता कि अमुक कार उसके व्यक्तिगत या सचिव ने किया है जत वे ही उदके लिए उत्तरदायी है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के साथ साथ हर मानी सामूहिक रूप से भी मित्रमण्डल के किया कलापा के लिए उत्तरदायी होता है। मित्रमण्डल एक इकाई है। विवानमण्डल एव समाट के साथ वाय व्यवस्था है। सभी मानी एक साथ एक इकाई के रूप में कार्य करती है। सभी मानी एक साथ एक इकाई के रूप में पर वहण करती है। एक माने के विच्छ आरोप पूरे मित्रमण्डल के विच्छ आरोप माना आता है।

^{15 &}quot;The Sovereign has, under a Constitutional Monarchy such as ours, three rights—the right to be consulted, the right to encour age and the right to warn' —Walter Bagehot The English Constitution, op ett., p 111

¹⁶ अविश्वास प्रस्ताव (Voice of No confidence) साधारणत विरोधी दल के नेता द्वारा मि त्रमण्डल की सामा य नीति या उसके समस्त कायकलाप के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाता है ।

लास्की के अनुसार, "मित्रमण्डल एक गुप्त निकाय है अत वह अपन निणयो के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायों है।"" मन्त्रिमण्डल नी वठका म सदस्या को स्वत न विचार-विमद्य का अवसर होता है पर तु एक बार निषय हो चुकन पर मित्रमण्डल नी कायवाही गुप्त रखी जाती है। 1878 ई म लॉड सेलिसवरी ने सामूहिक उत्तर दायित्व का निर्धारण करत हुए वहा था कि "मन्त्रिमण्डल के सभी निणया के तिए हर वह सदस्य जो त्यामपत्र नहीं दता, पूण एव अनिवायत उत्तरदायी है। उस बाद म यह कहने का अधिकार नहीं है कि वह किसी एक मामले म तो समभौत के कारण एव दूसरे में अप सदस्या के समभाने बुभान पर सहमत हो गया था। 28 अत हर मात्री को जो त्यागपत्र नहीं देता, मित्रमण्डल के निजयों को स्वीकार करना चाहिए अयया त्यागपन दे दना चाहिए।18 यदि वह त्यागपन नही देता तो मले ही उस निण्य का उसके द्वारा विरोध किया गया हो, वह उसका निणय माना जायेगा। उस निणय के पक्ष में उसे मित्रमण्डल म मत देना चाहिए एव आवश्यकता पडन पर जनता में उसका समयन करना चाहिए। यदि सदन म मतदान के समय कोई मात्री अनुपस्थित रहता है तो उसकी निया की जानी चाहिए और उस मिचमण्डल से निकाल दिया जाना चाहिए। मित्रमण्डल द्वारा स्वीकृत नीति के विरुद्ध किसी मात्री को कोई वक्तव्य नहीं देना चाहिए। यदि मिनमण्डल के निणय के विरुद्ध कोई मानी अपना वक्तव्य देता है तो उसे पदत्याग करना पडता है। उदाहरण के लिए, 1903 ई म चम्बरलन ने त्यागपन दिया था। इसी प्रकार किसी मी मानी द्वारा ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया जाना चाहिए जिसके सम्ब ध मे मिनमण्डल ने कोई निणय नही लिया हो । 1927 इ म सर विलियम जानीसन हिन्स द्वारा मित्रमण्डल के निषय के असाव में ही 21 वर्ष से अधिक आयुकी स्तियो को मतदान का अधिकार देने का वचन दिया गया या। मिनमण्डल ने जॉनीसन के इस आस्वासन को स्वीकार नहीं किया, फलस्वरूप उर्ह पदस्थाग करना पडा था। पर तु किसी घोषणा के पूत्र महत्वपूण सहयोगियो का सम

^{17 &}quot;The Cabinet is a secret body, collectively responsible for its decisions"—Laski Parliamentary Government in England, op at, p. 254

¹⁸ Quoted by Lasks Ibid, p 254

^{19 1855} ई में लींड जींत रसाज ने मीं प्रमण्डल के निषय से असहमत होने के कारण त्यागपन दिया था। जनरल पील ने तीन अ य सदस्यो सहित डिजरेली के सुधार कानून से असहमत होने के कारण त्यागपन दिये था। 1914 ई म लांड मों लें एवं थी नन ने मुद्र में शामिल होने के विचार का समयक होने के कारण त्यागपन दिया था। हरवट सेमुख्त एव अ य उदारवादिया एव थी स्नीडीन ने ओटावा सममौते के विरोध म त्यागपन दिया था। 1938 ई म थी ए योगी ईटन ने प्रधानम नी चम्बरलेन की विदेश नीति के विरोध म त्यागपन प्रस्तुत निर्मा था।

यन प्राप्त करने पर त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं होता है। उदाहरण के लिए, लायड जाज ने 1911 ई में में सन हाउस (Mansion House) मापण के पूत्र इस प्रकार का आस्वासन प्राप्त कर लिया था। कोई मात्री अपने बचाव में यह नहीं कह सकता कि मिनमण्डल के निणय से वह स्वय सहमत नही था।

सामूहिक उत्तरदायित्व का यह अथ नहीं होता कि कोई मंत्री कमी अकेले पदत्याग करेगा ही नही या सम्पूण मि श्रमण्डल प्रत्येक मात्री के व्यक्तिगत भ्रष्ट एव सावजनिक जीवन के उदात्त नैतिक मानदण्डो के विपरीत आचरण के लिए उत्तरदायी होगा। यदि कोई मन्त्री ब्यक्तिगत अयोग्यता, भ्रष्टाचार अयवा चारित्रिक दोप का अप राधी हाता है तो ऐसी अवस्था मे सम्पूण मिनमण्डल को पद-त्याग करने की आवश्यकता नहीं होती, अपित केवल उस मात्री विशेष को ही अपने पद से हटना पडता है। उदा-हरणार्थ, 1936 ई मे अथ मात्री जे एच टॉमस एव 1947 ई म डालटन को बजट के रहस्यों के पूल-प्रकाशन के कारण अपने पदों से त्यागपत्र देना पडा था। 1922 ई. म मारत-मानी मोटेग्यूको मित्रमण्डल से निष्कासित कर दिया गया था क्यांकि उ होन मित्रमण्डल की अनुमति के बिना महत्वपूर्ण नीति सम्ब धी प्रस्ताव की प्रकाशित करने का आदेश दे दिया था। 1937 ई में विदेशमात्री सेमुअल होर को इस कारण पदत्याग करना पडा था कि उनके एव फास के विदेश मानी लावेल के मध्य सम्पत्र इयोपिया सम्ब वी कुरिसत समभौता देश को माय नहीं था। व कीलर-काण्ड से सम्बिधित जॉन प्रोप्यूमा को अपने व्यक्तिगत भ्रव्ट चरित्र के कारण त्यागपत देना पढा था। प्रोप्यूमा ने कॉम स सभा मे जिस्टन कीलर नामक सु दरी से अपने सम्ब धो को अस्वीकृत करके असत्य भाषण किया था । इसी प्रकार सुदिरियो के कारण (मई 1973 ई मे) लॉड जेल्लिको एव लॉड लेम्बटन को त्यागपन देना पडा था।

सामूहिक उत्तरदायित्व के अमाव मे मिनमण्डल एक टीम के रूप म कार्य नहीं कर सक्ता। इसके अभाव मे मित्रमण्डलीय प्रणाली का काय-सचालन असम्मव ही जाता है। यदि सामूहिक उत्तरदायित्व को समाप्त कर दिया जाय तो समी मंत्रीगण अपनी-अपनी दपली तथा अपना-अपना राग अलापेगे। अत यह एक आवश्यक एव स्वस्य नियम है। सामूहिक उत्तरदायित्व परस्पर विश्वास को जम देता है एव नीति के सम्बाध में विचारों और सहयोग का आदान प्रदान सम्मव होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व के अभाव मे मित्रमण्डल का दीर्घजीवी होना सम्मव नही हो सकता। जनता की हृष्टि में अलोकप्रिय निषयों से सभी बचना चाहते हैं। 1932 ई म ब्रिटिश

²⁰ बाद की घटनाओं स ऐसा लगता है कि मित्रमण्डल बिदेश मंत्री के विचारा स सहमत था। सम्भवत यही कारण था कि वे पुन कुछ माह बाद नीसेना मंत्री बना दिये गये थे। अत कुछ समय के लिए उह नेवल बलि का बकरा बनाया गया था।



विकल्प रहते है प्रथम, पद से त्यागपत देना, एव द्वितीय, नवीन निवाचन की मांग करना । साधारणत प्रधानमन्त्री द्वारा द्वितीय विकल्प अपनाया जाता है । वह सम्राट से ससद के विघटन की माग करता है जिसे सम्राट सामा यत मान तेता है। यदि नवीन चनावों में मित्रमण्डल विजयी होता है तो वह पदारूढ रहता है। यदि चनावा म मित्रमण्डल पराजित होता है अर्थात नवीन चुनावो के परिणामस्वरूप मित्रमण्डल के दल को कॉम स समा में बहमत प्राप्त नहीं होता तो प्रधानमात्री तुरात अपन मात्र मण्डल का त्यागपन प्रस्तुत कर देता है। ससद के विघटन की माग के द्वारा प्रधान म तो यह मत ब्यक्त करता है कि इस कॉम स समाको मले ही मुक्त म या मर मित मण्डल में विश्वास न हो पर तुजनता का मैं आज भी विश्वासपान हूँ, जत मुक्ते सीधे जनता से अपने भाग्य का फैसला कराने का अधिकार प्राप्त है। अत वह निवा चन के माध्यम से जनता से कॉम स समा के निणय पर पूर्नीवचार की प्राथना करता है। साधारणत कोई भी मन्त्रिमण्डल अब कॉम स समा म पराजित होने पर पदस्याग नहीं करता।

कई विद्वाना की हरिट म सामृहिक उत्तरदायित्व की उपादेवता सादेहजनक है। इससे कॉम स समाका महत्व कम हुआ है एव उसकी स्थिति भी गिर गयी है तया मित्रमण्डल का अधिनायकत्व स्थापित हो गया है और मित्रमण्डलीय उत्तर दायित्व की आड म नौकरशाही फल फुल रही है। व्यवहार म मित्रमण्डल के विरुद्ध विदिवास का प्रदेशन सफलतापूचक कर सकता असम्भव नहीं तो अत्यधिक विठित हो गया है । यह मित्रमण्डल के दलीय स्वरूप के कारण है । मित्रमण्डलीय उत्तरदायित्य के दोप पर प्रकास डालते हुए मोर्लेन कहाथाकि विक्त मंत्री को विदरा मंत्री व गलत पत्र के लिए पद से हटना पड सकता है, तथा सुयोग्य यह-सचिव को मूल युद्ध मात्री **की भूला के परिणाम मो**गने पड सकते हैं। वहरमेन फाइनर का इन सम्बंध म मत है कि यदि मित्रमण्डलीय व्यवस्था के श्रेष्टतम अग्न की रक्षा करनी है ता हुम इसरा

मान । लेकिन घाँघली की अधिक गुजाइरा नहीं होती । यदि मित्रमण्डल क विगद्ध बहुमत होता है ता मित्रमण्डल की कॉमन्स समा म एक क बाद दूसरी हार हाती ही बली जायंगी।

^{25 &}quot; as a general rule, every important plece of departmental policy is taken to commit the entire cabinet and its members stand and fall together The Chancellor of the Exchequer may be driven from the office by a bad despatch from the foreign office and an excellent Home Secretary may suffer from the blunders of a stupid Minister of War The Cabinet is a unit—a unit as regards the Sovereign and a unit as regards the Legislature Its views are laid before the Sovereign and before the Parliament as if they were the views of one man It gives its advice as a single whole, both in the Royal closet and in the hereditary or the representative Chamber The first mark

ससद के समी सदस्यों को मतदान की स्वतानता दी गयी थी। उसके मयकर परिणाम हुए थे। यदि प्रत्येक मान्त्री को स्वत प्रतापुवक अपना मत व्यक्त करने की स्वत प्रतापुवक अपना मत व्यक्त करने की स्वत प्रतापुवक अपना मत व्यक्त करने की स्वत प्रताप्रदान कर दी जाय तो मिन्नमण्डलीय व्यवस्था का आधार ही समाप्त हो जावगा। सामूहिक उत्तरदायित्व के ब्याव का विकल्प कमजोर एवं अल्पकालिक मिन्नमण्डलें हैं जो सम्पूर्ण मिन्नमण्डलीय व्यवस्था को घ्वस्त कर देंगे। इसस मिश्रित मिन्नमण्डलों का निर्माण हो सकता है। डॉ अनिम्स के मत म इससे फासीवाद का माग प्रसन्त हो जावेगा।

हरबट मोरीसन का यत है कि शासन को एक इकाई के रूप म काय करना चाहिए अयथा शासन में दरारे पड जाने की सम्मावना रहती है और यह सुशासन के लिए हानिप्रद एव आत्मघाती प्रमाणित हा सकता ह । अत उनका कथन या कि सभी मात्री मित्रमण्डल के निणया से बेंधे है। यदि कोई सावजनिक रूप मा नित्रमण्डल के निणय का खण्डन करता है तो उसे त्यागपत देना पडता है। 1 न्यूमेन के अनुसार सामूहिक उत्तरदायित्व केवल मित्रमण्डल के सदस्या पर ही नहीं अपित ससदीय सचिवी सहित सभी मित्रयो पर लागू होता है। एल एस एमरी के अनुसार हमारी मित्रमण्डलीय व्यवस्था का सार ही मिनया का सामूहिक उत्तरदायित्व है। नीति सम्बधी समी निणय सम्प्रण मिनमण्डल के निणय समभे जाते है। ससद की स्वीकृति अपवा निदा का प्रभाव सभी पर पडता ह । यदि कोई प्रश्न महत्वपूण नीति से सम्बिध होता है तो ऐसी अवस्था म मित्रमण्डल पद-त्याग कर देता है। व लाड हेलशाम (Lord Hailsham) इसे जत्यधिक स्वस्थ सबैधानिक सिद्धा त मानते हैं। वे मिन मण्डल के सामूहिक उत्तरदायित्व को ब्रिटिश ससदीय शासन प्रणाली की सम्पूर्ण सरचना का के द्र मानते है। 23 लास्की का यह मत है कि सामा य काल म सामूहिक उत्तरदामित्व का रहस्य यह है कि मिनमण्डल की जहें दलीय प्रणाली में हैं। दलीय रूप के कारण मित्रमण्डल को उद्देश्य की एकता एव इस एकता को कायम रखने के लिए आवश्यक समयन प्राप्त होता है। दलीय समयन के कारण ही राजनीतिक एकरूपता सम्मव होती है और सामृहिक उत्तरदायित्व का त्रिया वयन साकार हो उठता है।

. मित्रमण्डल के विरुद्ध जविश्वास ⁴ व्यक्त होने पर मित्रमण्डल के समक्ष दो ही

²¹ Herbert Morrison Government and Parliament, 1954, p 60

²² Amery Thoughts on the Constitutions, p 70

²³ Laski op at , p 258

²⁴ कमी-कभी काम स समा म मिन्नमण्डल का बहुमत होने पर भी असावधानी या समयको के पर्याप्त सस्था म उपस्थित न होन के पारण पराजय हो जाती है। इसे आकिस्मिक हार (snap vote) कहते हूं। इसके कारण मिन्नमण्डल पदस्याण करन को वाम्य नहीं किया जा सकता। यह मिन्नमण्डल के निणय पर निगर होता है कि बाम स समा म किस हार को महत्वपूण और विसे महत्वपूण न

विकल्प रहते हैं प्रयम, पद से त्यागपन देना, एव द्वितीय, नवीन निर्वाचन की माग करना । साधारणत प्रधानमन्त्री द्वारा द्वितीय विकल्प अपनाया जाता है। वह सम्राट सं ससद के विषटन की माग करता है जिसे सम्राट सामा यत मान लेता है। यदि नवीन जुनावों में मिन्यण्डल विजयी होता है तो वह पदारूढ रहता है। यदि नुनावों में मिन्यण्डल राजित होता है अर्थात नदीन चुनावों के परिणामस्वरूप मिन्नण्डल में मान्यण्डल को कॉम सं समा में बहुमत प्राप्त नहीं होता तो प्रधानमन्त्री तुरत अपने मिन्र मिन्य में अर्थ को कॉम सं समा में बहुमत प्राप्त नहीं होता तो प्रधानमन्त्री तुरत अपने मिन्र मण्डल को त्यागपन प्रस्तुत कर देता है। सखद के विषटन की माग के हारा प्रधान मन्त्री यह मत व्यक्त करता है कि इस कॉम सं समा को वसे ही मुक्त में या मेरे मिन्र-एडल में विश्वास न हो परंतु जनता का मैं आज भी विश्वासपा हूँ, जत मुक्त सीधे जनता से अपने भाग्य का फैसला कराने का अधिकार प्राप्त है। अत वह निर्वाच्या के माग्य के फैसला कराने का अधिकार प्राप्त है। अत वह निर्वाच्या के अपने भाग्य का फैसला कराने का अधिकार प्राप्त है। अत वह निर्वाच्या के अपने भाग्य का फैसला कराने का अधिकार प्राप्त है। अत वह निर्वाच्या के अपने भाग्य का फैसला कराने के निणय पर पुनर्वचार की प्रायना करता है है। साधारणत कोई भी मिन्यण्डल अब कॉम सं समा में पराज्ञित होने पर पदस्याम मही करता।

माने । लेकिन घाँघली की अधिक मुजाइस नहीं होती । यदि मित्रमण्डल के विरुद्ध बहुमत होता है तो मित्रमण्डल की कॉम स समा मे एक क बाद दूसरी हार हाती ही चली जायेगी ।

as a general rule, every important plece of departmental policy in taken to commit the entire cabinet and its members stand and fall together. The Chancellor of the Exchequer may be driven from the office by a bad despatch from the foreign office and an excellent Home Secretary may suffer from the blunders of a stupid Minister of War. The Cabinet is a unit—a unit as regards the Sovereign and a unit as regards the Legula ture. Its views are land before the Sovereign and before the Parliament as if they were the views of one man. It gives its advice as a single whole both in the Royal closet and in the hereditary or the representative Chamber.

512 | आधुनिक शासनत त्र

त्याग नहीं सकते। यदि हम व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को प्रथम देते हैं तो इसका यह अमें होगा कि प्रत्येक मन्त्री को अपनी सुरक्षा हेतु सहयोगी मन्त्रियों के अपराप का पक्षापोपण करना पड़ेगा और परिषद म निर्मीकतापूबक एव स्पष्टता के स्थान पर रक्षा हेतु सजप रहना पड़ेगा। ऐसा इसिलए भी सम्मव नहीं है क्योंकि प्रशासन के कार्यों को हम पृथक पृथक रूप में विमाजित नहीं कर सकत। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से सन्तिगठहत की एकता परिषद की स्पष्टता एव उत्तरदायित्व का अयदिग्य निषारण नष्ट हो जायेग।।

मन्त्रिमण्डल का अधिनायकत्व [मन्त्रिमण्डल तथा ससद के सम्बन्ध]

मिनिमण्डल ससद के प्रसाद पयात पदारूढ रहता है। मिनिमण अनिवायत समद के मदस्य होते हैं। अत ससद एव मिनमण्डल म घनिष्ट सम्बंध होते हैं। ससदीय सम्प्रभुता के युग 19वी सदी में ससद ही यथाय म स्वामिनी थी और मित्र मण्डल उसका सेवक । परातु 19वी सदी की यह स्थिति आज 20वी सदी में नहीं रही है। राजनीतिक दलीय नियं नण के फलस्वरूप स्थिति विल्कृल उलट गयी है अधात स्वामी सेवक और सेवक स्वामी बन गया है। 20वी सदी की मन्त्रिमण्डलीय अधिनाय करव का युग कहते हैं। मित्रमण्डल की स्थिति काफी शक्तिशस्त्री हो गयी है, फलस्वरूप हम आज 'मित्रमण्डल के अधिनायकत्व' की चर्चा करने लगे हैं। बेनिस्स के अनुसार मिनमण्डल ही कॉम स सभा का नियानण करता है, न कि काम स सभा मित्रमण्डल का 1²⁷ सर सिडनी लो के अनुसार आजकल किसी भी मित्रमण्डल की कॉम स समा म हार नहीं हाती। काम स सभा के प्रस्ताव के फलस्वरूप 1895 ई में उदार दल की अपदस्य किया गया था। उसके पश्चात किसी सरकार का पतन अविश्वास के कारण नहीं हुआ। 1° रेमजे स्थोर ने यिनमण्डल की इस बढती हुई शक्ति की तीव आलोबता की है। उसका कथन है कि मित्रमण्डल सबशक्तियान है। सिद्धात की हिट से मिनमण्डल ससद के अधीन है पर तुवास्तव म वह ससद कर स्वामी है। ° एक निकाय जो इतनी शक्तियों का प्रयोग करता है, सिद्धा त म ही सवशक्तिमान कहीं जा सकता है मले ही वह अपनी सत्ता के प्रयोग में कितना ही असदाक्त क्यों न हो। बहुमत का समयन प्राप्त होने के कारण जनता का निय त्रण होते हुए मा उसकी

of the Cabinet, as that institution is now understood is united and indivisible responsibility "-Morley Life of Walpole 1913, pp 155 56

²⁶ Finer Theory & Practice of Modern Governments op at , pp 595-96

²⁷ Jennings Cabinet Government, 1959 p 473

²⁸ Jennings Parliament, 1939, p 120

²⁹ Ramsay Must How Britain is Governed 1951 (Ind Ed), p 62

स्पति अधिनायक की है। दो पीढिया पूत की अपेक्षा आज यह अधिनायकत्व कही

।धिक निरकुश हो गया है।³⁰

मित्रमण्डल की शक्ति के विकास में दलीय अनुशासन, मित्रमण्डलीय उत्तर-तियत्व का सिद्धात्त, प्रदत्त विघि निर्माण, प्रशासकीय याय, मी प्रमण्डल की कॉमन्स तमा को विषटित करने की शक्ति एव ससदीय जीवन की वतमान दशा रूपी विभिन्न

तत्व प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं । इनका विश्लेषण निम्नवत है

(1) ब्रिटिश ससदीय सदस्यो पर राजनीतिक दलो का नियात्रण 19थी सदी की अपेक्षा बतमान सदी मे बढ गया है। आज निर्वाचित प्रतिनिधि अपने दल के निर्दे-शन पर पूरी तरह काय करता है। 19वीं सदी में विभिन्न अवसरों पर काम संसा म जिस उच्चकोटि का वाद विवाद हुआ करता था उसका अब अमाव है एव बहुत ही क्म अवसर पर वह देखन को मिलता है। लास्की के अनुसार वह भी केवल उन अवसरापर जब सरकार कॉम स समा के सदस्यों को स्वतान मतवान का अधिकार प्रदान कर देती है। दलीय प्रणाली की कठोरता का अय कॉम स समाका मित्रमण्डल पर नमश वढता हुआ निय प्रण है। इसका रहस्य यह है कि सत्ताल्ड एव विरोधी दल, दोना के ही नेता दलीय मशीन द्वारा अपने सदस्यों के कियाकलापो पर निय नण करत है। स्वतात्र सदस्यों के दिन अब बीत चुके हैं और उनके लौटने की कोई सम्मा-वना भी नहीं है। 31

दला की शक्ति मे वृद्धि मुख्य रूप से निम्न कारणो से हुई है

(क) मतदाताआ की सरया में वृद्धि हो जाने के कारण उनके जन सम्पक हेंदु अपेक्षाकृत कही अधिक व्यापक दलीय सगठन की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति म दला की शक्ति म वृद्धि होना स्वामाविक है।

(स) राज्य के काय क्षेत्र में विद्ध के फलस्वरूप संसद के शासकीय काय क्षेत्र म भी बद्धि हुई है। निर्धारित समय के अदर काय समाप्त करने के लिए अपेक्षाकृत

अधिक इढ एवं कठोर दलीय सगठन अपक्षित होता है।

(ग) वतमान निर्वाचक अपने प्रतिनिधियो को उनके व्यक्तिगत कार्यों की अपसा अधिकतर उनके दलीय नेताआ के कारण चुनते हैं। बहुत कम सदस्य जपनी योग्यता एव कार्यों के कारण चुने जाते है।

सास्की ने इसी स दम म यह कहा है कि सम्पूण दलीय पद्धति का व्यवसायी करण हो गया है एव उनके कार्यों की व्यापकता ने दलों को सेना के समान अनुसासन रखने के लिए विवश कर दिया है। यह सम्मव है कि दलीय कठोरता के विरुद्ध आवाजें उठें और विद्रोह मी हो । लेकिन अधिकादा सदस्य यह जानत हैं ति दल सं

³⁰ Ramsay Muir op cit p 68

³¹ Laski Parliamentary Government in England op eit , p 74

सम्बाध तोडना उनके लिए नेचल खतरनाय ही नही है प्रत्युन् विवाद के गम्भीर हान पर विरोधिया से भगडे के अवसर वढ जाते हैं। अत जब तन गोई गम्भीर बात नहीं होती, वल के आदर विद्रोह का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। स्मरणीय है 1931 ई म दल के नेचल 16 सदस्या ने रेमजे मैकडोनटड का साथ दिया था। 12

(2) मित्रमण्डलीय उत्तरसायित्व ने सिद्धात के कारण भी मित्रमण्डल की शक्ति मे विद्ध हुई है। सम्भूण मित्रमण्डल एक टीम के रूप म एव दूसरे के साथ सहयोगपूबक काथ करता है। मित्रमण्डलीय उत्तरसायित्व के फास्वरूप नौकरसाही में अनुसरदायित्व पनपता है। दसीय सगठन इसमें सहायक है। बहुमत के बूते पर मित्रमण्डल निरुद्ध हम से आवरण करता है।

(3) प्रवत्त विधि-निर्माण (Delegated Legislation) के उदय एव विश्वत में भी मिनमण्डल की शिवत म वृद्धि की है। राज्य के कार्यों म वृद्धि होन के कारण ससद द्वारा एक बड़ी सक्या म प्रति वप विधियां का निर्माण किया जाता है। समया मान एव अनेकानेक प्रकार से सम्बंधित विधियां की पेषीविष्यां के कारण सबद सम्बंधित विधियां की पेषीविष्यां के कारण सबद सम्बंधित विधियां की पेषीविष्यां के कारण सबद सम्बंधित विध्यां की प्रवास का प्रतास का प्रतास विध्यां की प्रवास का प्रतास का प्रवास विध्यां की प्रतास कर विश्वते हैं। ससद द्वारा विध्यकों के प्रारूप या मुख्य सिद्धान्तों को पारित वर दिया जाता है और सम्बंधित विमाण के मात्री को तत विध्यक सम्बंधी आदेश आवश्यकतानुसार जारी करने का अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। इस प्रकार अनिमण्डल के सदस्यों को विधि निर्माण की शनित प्रार्म हो जाती है। प्रति वण हजारा की सक्या म प्रशासकीय आदश जारी किये जाते हैं। अत प्रशासकीय को के अतिरिक्त मिन्यां को विधि निर्माण के सम्बंध म मी ब्यापक अधिकार प्रान्त हो गये है।

(4) यही स्थिति याय के क्षेत्र मे है। प्रशासकीय याय के कारण मित्रया के प्रमान एव शनित मे असाधारण वृद्धि हुई है। विमिन्न मात्रालयों को अपने विमान से सम्बिचत कुछ ऐसे मामला माया करने की शनित प्रदान कर दी गयी है जिन्दी सम्बाध म पहले न्याय करने का अधिकार सामान्यत वायालयों की प्राप्त होता या है। वार्ष । इस प्रमान्यत विमानीय मित्रयों को इससे व्यापक यायिक शनित्या प्राप्त हो गयी हैं। इन प्रशासकीय यायाधिक सन्तया प्राप्त हो गयी हैं। इन प्रशासकीय यायाधिक स्वाप्त को कार पढ़ित का अपनाने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्राकृतिक याया के नियमा का पालन इनसे अपेक्षात है।

(5) मी नमण्डल की सनित म वृद्धि का एक अय कारण उसनी ससर की विषटित करने की शनित है। मित्रमण्डल के विषद्ध अविश्वास व्यक्त होने पर उसे तत्काण त्यागपत्र देने की आवश्यक्ता नहीं है। प्रधानमात्री को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सम्राट (राज्याध्यक्षा) से मित्रमण्डल को विषटित करने की मौंग करें। जब

³² Laski op at p 74

सम्राट से प्रधानम त्री तत्सम्ब घी माग करता है तो राजा ससद को विघटित कर देने की उसको माग को स्वीकार कर लेता है क्यांकि ऐसा अग्तिसमय है। नवीन निर्वाचनो म विजयी होने पर ही मित्रमण्डल पदारूढ रह सकता है। स्पप्ट है कि मित्रमण्डल को ससद के विघटन की शक्ति के रूप म ब्रह्मास्य प्राप्त है। बेजहोट के अनुसार मित्र-मण्डल एक ऐमा जन्तु है जिसम अपने निर्माताओं को ही नष्ट करने की सक्ति होती है। ³³ विद्रोही ससद सदस्यो पर इस शक्ति के फलस्वरूप मिनमण्डल निय तण रखने म सफल रहता है। यह सम्मव है कि ससद के विघटित होने के पश्चात होने वाले निर्वाचना मे अनेक ससद सदस्य जनता द्वारा न चुने जाये । इसम उनका बहुत सा षन भी व्यय होता है।³⁴ अत विघटा की माँग करने की श्रक्ति के कारण मिनमण्डल की स्थिति काफी इंढ हो गयी है।

(6) ब्रिटिश ससदीय जीवन स्तर भी ससद पर प्रभावशाली नियानण रखने म नसफल-सा है। ससद के सदस्या को जनेक काम होते है। वे अपना पूरा समय सस दीय कार्यों को नही दे पाते । सिडनी लो³⁵ के अनुसार "आघा सदन कायरत रहता है तो आघा जामोद प्रमोद म व्यस्त ।" ससदीय प्रणाली मे मित्रमण्डल निरकुश हो गया है। मिनमण्डलीय प्रणाली एसा निरकुशतात्र है जा निरातर जनता की आलोचना ए दग्ध और जनमत, विश्वास का अमाव एव निवाचनो से आतिकत रहता है। ससद के सनकालों में ही मिनमण्डल उसके प्रति उत्तरदायी होता है। स्मरणीय हे कि 6 माह एव उससे अधिक समय तक ससद का कोई सन ही नही होता। रोजवेरी के अनुसार इस अविधि म समाचार पत्री से प्राप्त सूचना के अतिरिक्त हम तिनक भी यह पता नहीं रहता कि हमारे शासक क्या कर रहे हैं ? वे क्या प्रवाध एव तत्सम्बाधी विचार करते हैं ?36

अत साराश में मित्रमण्डल पर कॉम स का स्वामित्व कम हो गया है। मित-मण्डल अपन सदस्यों के बहुमत के बूते पर जो चाहे कानून बना सकता है, जितना चाहे जतना यय स्वीकृत करा सकता है, चाहे जो कर लगा सकता है एव जिस कर को चाहे समाप्त कर सकता है। ससद का जीवन उसकी मुद्री मे है। मित्रमण्डल व्यवहार म कॉम स समा का स्वामी ह। ससद मिनमण्डल के हाथ की कठपुतली बन गयी है। रैमजे म्योर के अनुसार, "नीति निर्घारण शासन, विधि निर्माण, आय-व्यय, उच्च पदा

³³ Bagehot The English Constitution op cat, Chap I, pp 59 81

³⁴ जेनिंग्स का कथन है कि ससद सदस्या को पुनर्निवाचन पर करीव 1 हजार पौण्ड तक ब्या करना पडता है। "He has to spend an unpleasant fortinght or three weeks Above all he may have little certainty of being re elected "—Jennings Parliament, 1939, p 112

³⁵ Sidney Low The Governance of England p 63

³⁶ Ibid

पर नियुग्तियाँ आदि काय मन्त्रिमण्डल के हाथ म हैं। " ब्रिटिश प्रजात व विरुत ह गया है। जनप्रतिनिधिया व हाथा म स निय त्रण की शक्ति उपरोक्त कारणा र खिसक कर मित्रमण्डल के हाथा म पहुँच गयी है और मित्रमण्डल अब स्वयं संसद के नियात्रित करने लगा है। यह विषयय ही मात्रिमण्डलीय अधिनायशत्व कहा जात है। लेकिन जेनियस का मत है कि मित्रमण्डल की उपरोक्त आलाचना का यह बय नहीं है कि जिस मित्रमण्डल का ससद का बहुमत प्राप्त हो जाता है उसका अस्यार्य अधिनायक्त्य स्थापित हो जाता है। वह जन मावना की उपदाा नही कर सकता। प्रो हेराल्ड लास्की एव श्री एल एस एमरी न मित्रमण्डल क अधिनायक्त क भारोपा का सण्डन विया है। व ब्रिटिश मित्रमण्डल की काय-पद्धति की उचित मानत हैं।

लास्की न आरोपा की ब्यापन समीक्षा नी है। 39 रेमजे स्योर के जनुसार मित्रमण्डल अपन निम्न दायित्यों का मली प्रकार निमान म असमय है। प्रशासनत न की समीक्षा तथा नियात्रण, एव विभिन्न विभाग के कार्यी म समन्वय । इन दायित्वा के ससद सं मिनमण्डल को हस्तान्तरित हो जान क परिणाम अत्यात घातक हुए है। लास्की का मत है कि प्रत्यक मात्री मित्रमण्डल का सदस्य हाता है। उनक निणया ने पीछे मित्रमण्डल की सत्ता हाती है। मित्रया का नवीन समस्याओं पर विचार करने एव तत्सम्बाधी विचाराको मित्रमण्डल म रखन की पूण स्वतात्रता होती है। वित्तीय प्रश्नो पर वित्त विभाग म पुण विचार विमद्य होता है। विवादास्पद विषया पर मित्रमण्डल विचार एव निणय करता है। ससद स्वय एक वृहद् निकाय है और वह प्रशासन पर नियाप्रण सम्बाधी दायित्वा को मली प्रकार नहीं निमा सकती। अत प्रशासन पर निय तण सम्बाधी किसी अाय श्रेष्ठ प्रणाली की बतमान मीतमण्डलीय नियात्रण पद्धति की तुलना म कल्पना करना कठिन है। रेमजे स्योर का यह भी तक था कि मिनिया के पास न तो समय है और न ही पर्याप्त अवकाश है कि वे तकनीकी एव आर्थिक प्रश्नो का सुलक्षा सके। उनके पास उस आवश्यक क्षमता का भी अभाव है जो इन प्रश्नो को हल करने के लिए आवश्यक है। लास्की का कथन है कि ये विचार ठीक है परातु मित्रमण्डलीय पद्धति पर रेमचे म्योर केय आरोप गलत हैं। मि त्रमण्डल राजनीतिक सतह पर उभरने वाली समस्याओ पर ही विचार कर सकता है । मित्रमण्डल—राजनीतिज्ञो का समूह—विशेषभो का सगठन नही है। न वे शोधकर्ता हैं। मनित्रमण्डल का काय तो शोध के परिणामो नाठीक ढग से प्रयोग करना है। ससदीय लोकतात्र मे शासन को वही काय करने चाहिए जिनकी मतदाताआ का अपेक्षा-कृत वडा समूह उससे अपक्षा करता हो। मिनमण्डल रॉयल सोसाइटी की मौति

³⁷ Ramsay Muir op cit, pp 66 69 38 Jennings Cabinet Government, op cit, pp 475 476 39 Laski Parliamentary Government in England, op cit, pp 262 305

ज्ञानाजन करन वाली सस्था नहीं है। उसका काय तो तात्कालिक राजनीतिक महत्व से सम्बन्धित परिणामो के उपयुक्त प्रयोग से सम्बन्धित है।

मिं प्रमण्डल के लिए लोकमत की उपेक्षा करना असम्मव है। ससदीय प्रणाली में सासक अधिनायक नहीं होता एवं वह लोकमत से स्वत न होकर नीतियों की पोपणा नहीं कर सकता। 10 उसे अपने प्रस्तावों को किया वित करने के लिए सहयोग को आव रयकता होती है और इस सहयोग को प्राप्त करने के लिए सासन को दल को आजाओं का सदेव घ्यान रखना पडता है। ससदीय प्रणाली का सार उत्तरदायित्व है। उत्तर-दायित्व के अतिरिक्त किसी अय विकल्प को स्वीकार करने के फलस्वक्प सम्पण्य प्रणाली ध्वस्त हों जायगो। यही नहीं वासकीय कार्यों का दायित्व ससद के बाहर किसी अय सस्या को सौपने का अब अधिनायकत्व के लिए माय प्रशस्त करना है। अत विकाश स्वाप्त के सार करना है। अत विकाश से सार स्वाप्त के स्वाप्त करना है। इसका यह अप है कि की तमप स्वाप्त के सार उत्तर-वायित्व निष्तानित होकर मतदाताओं के प्रति हो या है। पहले मंत्री सम्राट के प्रति उत्तरदायों होते थे। लोकत त्र के थोडे विकास के कारण मिनमण्डल काम स समा के प्रति उत्तरदायों होते हो गया था तथा लोकत न के पूर्ण विकास होने पर मिनमण्डल अव सी वे जनता के प्रति उत्तरदायों हो गया था तथा लोकत न के पूर्ण विकास होने पर मिनमण्डल अव सी वे जनता के प्रति उत्तरदायों हो गया था तथा लोकत न के पूर्ण विकास होने पर मिनमण्डल अव सी वे जनता के प्रति उत्तरदायों हो गया था तथा लोकत न के पूर्ण विकास होने पर मिनमण्डल अव सी वे जनता के प्रति उत्तरदायों हो गया है। गया है। पर सि विकास के प्रति उत्तरदायों हो गया है। व्याप्त हो गया है।

एल एस एमरी की मिन्न तक दिय है। उनके अनुसार लाकत नीय सासन पद्धित के दो सिद्धान्त है। प्रथम सिद्धा त यह है कि सरकार को शासनाधिकार जनता से प्राप्त होता है। अत शासन का चुनाव जनता या उसके प्रतिनिधिया द्वारा ही होना चाहिए और जनता की इच्छानुसार उसके आदेशा का अनुसरण करत हुए ही सासन किया जाना चाहिए। कास, स्विट्जरलण्ड एव समुक्त राज्य अमेरिका म इसी सिद्धात को मा यसा दी गयी है। अमेरिकी राज्यपित जो कायपालिका का प्रमुख है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष कप से चुना जाता है। ततीय फ्रेंच गयराज्य का राज्यदित जनता द्वारा चुना जाता है। ततीय फ्रेंच गयराज्य का राज्यदित जनता द्वारा चुना जाता था और पांचव क्रेंच प्रयाज्य म भी जनता द्वारा ही चुना जाता है। व स्वत न रीति से शासन का सचालन नहीं कर सकते। पराष्ट्र प्रेट प्रिटन क शासन

⁴⁰ लोकमत की उपेक्षा के परिणाम नयकर होत हैं। 1886 ई म आयरित स्वराम्य के प्रस्त पर उदार दल एव 1931 ई म ब्यय की कमी के प्रस्त पर मजदूर दल का पतन हो गया था। 1936 ई म नेमुजल होर को अवीसीनिया सम्बन्धी उनकी नीति के लोकमत के प्रवल विराध के कारण ही त्यागपत्र देता पढ़ा मा। प्रभागम त्री ईडन की स्वेज नहर पर आतमण की नीति की जनता ने तीप्र निदा की थी, फलस्वरूप उद्द राजनीति से अवकारा ग्रहण करना पढ़ा था।

⁴¹ Laski of cit, pp 277-278
42 L S Amery Thoughts on Constitution, of cit Chap I, pp 1 32, Chap III, pp 70 104

के सगठन का सिद्धा त इससे मित्र है। वहाँ शासन या मित्रमण्डल का निर्माण सम्राट द्वारा किया जाता है। उसके अधिकारा का मूल त्रिटन का राजा होता है, न कि जनता या उसवे प्रतिनिधि । ब्रिटिश मिनमण्डल जनता या उसके प्रतिनिधियो द्वारा निर्वाचित नहीं है, अपितु ब्रिटिश प्रधानमात्री की नियुक्ति सम्राट करता है एव उसके परामश से अय मनियोः की नियुक्ति की जाती है। अत शासन सचालन म मित्रमण्डल ससद का अनुकरण न करक उसका नेतृत्व करता है। लाकतात्र वा ग्रेट ग्रिटेन मयह अय है कि शासन ससद की सम्मति से होना चाहिए, न कि ससद द्वारा स्वय शासन किया जाय । जिटन मे न तो ससद स्वय शासन करती है और न वह कर सकती है । नीति निर्धारण एव शासन सचालन का अधिकार नेवल मन्त्रिमण्डल को प्राप्त है। ससद केवल सहमित या असहमित व्यक्त कर सकती है। ससद की असहमित पर ब्रिटिश मित्रमण्डल पदस्याग कर देता है परातु वह अपनी नीति म कोई परिवतन नही करता। मिनमण्डल सदैव ही नेतृत्व करता है। ससद को किसी न किसी मित्रमण्डल के पीछ चलना ही पडता है। एमरो के कथन का साराश यह है कि ब्रिटिश पद्धति म प्रमुखता मिनमण्डल की है। ससद का काय केवल आलोचना करना और नियानण रखना है। मुख्य बात यह है कि शासन का सचालन होता रहे--शासन सचालन जनहित म ही, यह बाद की बात है। जिन देशों म ससदीय प्रणाली के इस सिद्धात के कम को बदलकर लोकतात्र को प्रधान एव शासन को गीण स्थान दिया गया है वहा ससदीय पद्धति मे अनेक दोप उत्पत्न हो गय हैं, यथा-मिनमण्डल निवल एव अल्पजीवी हो गये हैं। अत मित्रमण्डलीय उत्तरदायित्व का विशुद्ध अथ यह है कि यदि मित्रमण्डल की नीति से जनता या ससद सहमत नहीं है तो मित्रमण्डल को पदस्याग कर देना चाहिए। पर तु जब तक ससद या जनता उसको पदारूढ रखना चाहती है उस समय तक वह उसमे निरत्तर विश्वास व्यक्त करती रहती है । ऐसी स्थिति मे मित्रमण्डलकी अपने पद पर बना रहना चाहिए एव ससद को मित्रमण्डल का नेतृत्व मानते हुए कार्य करना चाहिए। अत मित्रमण्डल की निरकुशता एव तानाशाही की चचा उनके द्वारा की जाती है जो मिनमण्डलीय उत्तरदायित्व के इस अथ को नहीं समभत । जनता स्वय शासन सचालन नहीं कर सकती। अधिक से अधिक वह यह बता सकती है कि शासन अच्छा है या नुरा । यह ब्रिटिश ससदीय प्रणाली का मौलिय एव जाधारभूत सत्य है ।

व्यवहार मे मि प्रमण्डल पर लोकमत का सदव ही निय प्रण रहता है। लोकमत की उपेक्षा करने का साहुए शक्तिशाली से शक्तिशाली मि प्रमण्डल भी नहीं कर सकता है। यदि कोई मि प्रमण्डल बार बार त्यागपत्र देता है या ससद के विषटन की मीग करता है या जनमत की उपक्षा करता है एव अत्यधिक गोपनीयता वरतता है तो उसके अलोकप्रिय हो जाने का भय है। उसे सदव हो जनता की इच्छा एव अपन समयका के हिंता की घ्यान रखना चाहिए और जनहित म ग्रासनीय नीति को आवश्यकतानुसार तुर त परिवर्तित कर देना चाहिए अयया परिणाम नयकर हो सक्ते हैं । 1931 ई मे श्रमदलीय मि श्रमण्डल को अपन सहयोगिया—स्नाडीन, वॉमस एव हे डरसन के विद्रोह ने कारण ही पदत्याग करना पडा था। ⁶³ 1934 इ की राष्ट्रीय सरकार की, जिस काम स म असाधारण बहुमत प्राप्त था, बेराजगार सहायता अधिनियम के कारण पद त्याग करना पड़ा था। 1935 ई म कुत्सित होर लावेल पक्ट के कारण विदेश म नी संमुजल होर को पदत्याग करना पडा था। 1937 ई में चम्बरलेन की गलत विदेश नीति का जनता न विरोध विया, फलस्वरूप उन्ह जपन पद स हटना पडा था। स्वेज नहर क प्रश्न पर प्रधानमात्री ए योनी ईडन को प्रधानमात्री पद स हटना पडा यद्यपि उनके दल का बहुमत था। यह सब उदाहरण इस मत की पुष्टि करते है कि मिनिगण्डल को जनता की नाडी पर सदैव ही हाथ रखना चाहिए। जनता के विरोध म मित्रमण्डल का अत्त निद्यित है। अत लावेल 44 का यह कथन पूणरूपेण सत्य है कि मित्रमण्डल की निरकुराता का कारण सावजनिक लोकप्रियता है, उसकी निरतर ही आलाचना होती रहती है तथा जनमत की शक्ति, (सदन के) विश्वास की आवश्यकता एव नवीन निर्वाचना की सम्मावना सदव ही उस (मित्रमण्डल) का व्यवस्थित करती रहती है। मित्रमण्डल भी आलोचना के प्रति सदैव सजग रहता है एव उसकी क्मी उपक्षानहीं कर सकता। फाइनर का निम्न मत ब्रिटिश मित्रमण्डलीय प्रणाली के सादम म महत्वपूण है "ब्रिटिश मित्रमण्डलीय व्यवस्था की घ्रगामी, गतिशील, विवकी एव उत्तरदायी नतृत्व प्रदान करती है। इस पर नियानण रखा जा सकता है परतु इसका दमन सम्भव नहीं है। इससे प्रश्न किये जा सकते हैं परतु इसका अविश्वास नहीं किया जा सकता। राजनीतिक द्वेष होत हुए भी इसके सदस्या म व्यक्तिगत इच्यों नहीं होती । इस पर उत्तरदायित्व की शक्ति, इसकी सस्थाओं एव अनुमतियो द्वारा नियात्रण रखा जा सकता है।"45

विदिश प्रधानमन्त्री

मोर्ले के अनुसार ब्रिटिश प्रधानम त्री मित्रमण्डलीय मेहराब की जाधारशिला

⁴³ स्मरणीय है 1931 ई में कॉम स म दलीय स्थिति निम्नवत थी अनुदार दल-260, उदार दल 59 एव श्रम दल 288। इस समय रेमजे मनडोनल्ड प्रधानम त्री य । हे डरसन के नेतृत्व म कुछ अमदलीय सदस्या ने विद्रोह कर दिया। फल स्वरूप मित्रमण्डल का पतन हो गया था।

⁴⁴ Lowell The Government of England, Vol I, p 355

⁴⁵ Finer op cat, p 621 46 The Prime Minister is the Leystone of the cabinet arch"—Lord Morley Life of Walpole (1913) cited by Ramsay Muir op at , p 63

520 | जाधुनिक शासनत व

है। "ययपि मिन्नमण्डल के सभी मिन्नया ना स्तर समान होता है और वे सभी एक स्वर म बालते हैं तथा मतदान के समय 'एक व्यक्ति एक मत' के अनुसार मतगणना नी जाती है परानु मिनिमण्डल का अध्यक्ष अपन समकक्षा म प्रयम (primus inter pares) होता है। वह अपने पद पर रहते हुए असाधारण एव विवित्र मता का उपयोग करता है।" विविद्यम यनींत हुरकोट के अनुसार वह तारों के मध्य चादमा है। धुनरों के अनुसार यह कोई नहीं जानता कि अध्य मन्त्री कहीं 'एहं है। पर मुख से मूख मी जानता है कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट का क्या अध्य है। कि प्रयाम भी मित्र परिषद, प्रित्मण्डल एव द्यासन का प्रमुख होता है। साइको के अनुसार बिटिश प्रधानमन्त्री मित्रमण्डल के निर्मण, उसके जीवन एवं मुखु के लिए के द्रीय स्थित रखता है। " रेमजे म्योर की हिन्द म मित्रमण्डल राज्य स्पी जहांज का बालक वक है और प्रधानमन्त्री उसका चातक है। "

प्रधानमन्त्री मि त्रमण्डल का प्रमुख एवं द्वासन का प्रधान होता है। विदिध प्रधानमन्त्री का पद विकास का परिणाम है एवं अभिसमय पर आधारित है। हतीवर वध के काल में प्रधानमन्त्री के पद का उच्च हुआ था। बाँज प्रमम जमन नापा नहीं जानता था। उसने मि त्रमण्डल की बैठका की अध्यक्षता करन लाय था। वर्रच जानता था। उसने मि त्रमण्डल की बैठका की अध्यक्षता करन लाय था। वर्र वालपीत प्रमम प्रधानमन्त्री थे। विदिश प्रधानमन्त्री का 1905 ई में दासकीय कानवातों में प्रयम मार उल्लेख मिलता है। इस वप एक राजधीएणा कं अनुसार याक के आकविषय के पदचात जसे वरिष्ठता प्रदान की गयी थी। विद्या प्रधानमन्त्री को First Lord of Treasury (कीवागार के प्रयम लाँड) के रूप में वेतन मिलता था। 1937 ई में त्राजन एकर (Ministers of Crown Act) के हारा प्रधानमन्त्री एवं कोपागार के प्रयम लाँड के वेतन का स्थन्द उल्लेख करने स्थन्द उन्हें से प्रधानमन्त्री को विधिक मां पर्ण

⁴⁷ Ibid , p 157

^{48 &#}x27;Inter Stellas Luna Moners'-Sir William Vernon Harcourt cited by Ogg and Zink op ett. p 90

^{49 &#}x27;No one knows and no one cares where other Ministers dwell but the fool of fools knows the meaning of the 10 Downing Street' —Munro The Governments of Europe, 1954 p 75

[—]Munro The Governments of Europe, 1954 p 75
50 'The Prime Minister is central to its formation, central to its life and central to its death —Lash: Parliamentary Covernment in

England pp 228 229
51 The cabinet is in short the streering wheel of the ship of the state the stereman is the Prime Minister —Ramsay Mur How Britain is Governed, op cit, p 63

⁵² इसस पूत्र बिना सिंघ म डिजरेली (लॉड बैक सफील्ड) को First Lord of Her Majesty's Treasury and Prime Minister कहा गया था।

प्रदान की गयी है। उसे 10 हजार पौण्ड प्रति वय वेतन प्रदान किया जाता है तथा समस्त भूतपुर प्रधानमन्त्रिया को 2 हजार पौण्ड प्रति वय पेशन के रूप में प्राप्त हात हैं।

ब्रिटिश परम्परा ने अनुसार प्रति नवीन निर्वाचन के पश्चात सम्राट काम स समा के बहुमत दल के नता को प्रधानमात्री के पद पर नियुक्त करता है। 53 ग्रेट ब्रिटेन म दिदलीय पद्धति हान के कारण सम्राट को बहुमत दल के नेता को चुनना कठिन काय नहीं है, परन्तु तीन या अधिक दला के विकसित होने पर कठिनाई उत्पन हा जाती है। कॉम स समा म बहुमत दल क नता की स्थिति अस्पष्ट होन की दशा में ही प्रधानमन्त्री के चयन म सम्राट को स्वधिवेकीय शक्ति प्राप्त होती है। 1894 ई म प्रधानम त्री ग्लेडस्टोन के स्यागपत्र क पश्चात उदार दल का कोई स्पष्ट नेता नहाने की स्थिति म सम्राट ने स्वविदेश से प्रधानमात्री का चयन किया था। सम्राट द्वारा एस ध्यक्ति को ही प्रधानमात्री के पद पर चुना जाना चाहिए जो स्थामी शासन ना निर्माण कर सके तथा कॉम स समा वा विश्वास ऑजत कर सके । जब काम स मेंना में दला की अस्पट्ट स्थिति के फलम्बरूप प्रधानमानी का चयन करना असम्मव होता है ता सम्राट या राजा का इस सम्बाध में स्विवविकीय शक्ति प्राप्त हो जाती है। 1931 ई म श्रमदलीय प्रधानमात्री रमजे मक्डोनल्ड को श्रम दल से निष्कासित करके हं डरसन को दल का नेता चुना गया था। कॉम स म थम दल के 289 सदस्यो में से 16 सदस्या न विद्राह कर दिया था। देश की वित्तीय कठिनाइयो को दूर करने के सम्ब ध म प्रस्तादित उपाया पर मित्रमण्डल म उत्पत्र मतभेद विद्रोह का कारण या । 23 अगम्त, 1931 ई को रेमजे मैनडोनल्ड ने पदत्याम कर दिया। सामा य परिस्थितिया म प्रधानमानी के पदत्याग करने पर राजा को कुछ निश्चित अभिसमया के अनुसार विरोधी दल के नेता को नवीन मित्रमण्डल के तिर्माण हेतु आमि त्रत करना चाहिए । अत रेमजे मनडोनल्ड के पदत्याम के पश्चात या तो अनुदार दल के नेता बाल्डविन का या श्रम दल के नय नेता है डरसन को प्रधानम नी पद के लिए आम-ित्रत करना चाहिए था। पर तु सम्राट जॉज पचम न रेमजे मक्डीनल्ड से वित्तीय सक्ट-काल में राष्ट्र का साथ देने की अभील की एवं अनुवार और उदार दल के जीत-रिक्त थम दल के जन समी सदस्या का सहयोग राष्ट्रीय सरकार के निर्माण हेतु प्राप्त करने का प्रयत्न किया जो उसके लिए तयार थे । ऐसा विश्वास किया जाता है कि राजा ने जनुदार एवं श्रमदलीय नेताओं से भी एसी ही अपील की थी।" फल म्बरूप रेमजे मक्डोनल्ड को पून प्रधानम ती चून लिया गया और उ होने राष्ट्रीय सर

⁵³ महारानी विकटोरिया ग्लेडस्टोन को व्यक्तिगत रूप के पस द नहीं करती थी परन्तु ज है ग्लेडस्टोन की बहुमत दल का नेता होने के कारण चार बार प्रधान मनी पद पर आमित्रत करना पड़ा था।

⁵⁴ Mr Sidney Webb (Colonial Secretary in Mr Macdonald's Cabi net) quoted by Laski op ett, p 234

कार का निर्माण किया। लास्की के अनुसार राजा के द्वारा रमजे मक्डोनल्ड को प्रधानमात्री पद के लिए तैयार करना उसके सवधानिक दायित्व के अनुरूप नहीं था। "नवीन मन्त्रिमण्डल का स्वरूप राजमहल की कात्ति के सदृश्य ठीक उसी प्रकार था जैसे कि 1763 ई मे लॉडवूट को प्रधानमात्री बनाया गया था।"⁵ लास्की का मत है है कि रेमजे मनडोनल्ड को राष्ट्रीय सरकार का प्रधानमात्री बनाना सवया अनुनित या क्यों कि वे दलीय प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री नहीं बने थे। दल ने उह नेता पद से निष्कासित कर दिया था। अत उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर मक्डी नल्ड की नियुक्ति वस्तुत राजा की इच्छा का परिणाम थी। स्मरणीय है कि सिडनी वेब एव जेनिग्स ने सम्राट जॉज पचम के काय को पूणरूपेण सवधानिक ठहराया है क्यों कि उदारवादी नेता समुअल तथा अनुदारवादी नेता वाल्डविन दोनो ने आमितित किये जान पर मनिमण्डल का निर्माण करने से इकार कर दिया था। अत राजा द्वारा मैक्डोनल्ड के असिरिक्त किसी अय को नियुक्त करने का विकल्प नही था। परंतु राजा द्वारा हे डरसन को मन्त्रिमण्डल के निर्माण हेतु आमितत न करने का काई जीचित्य नहीं था। लास्की ने इस सम्पूण घटना से यह निष्कप निकाला है कि अस्थिर राजनीतिक सकट के समय प्रधानमानी के चयन म राजा का महत्व अत्यिधिक हो जाता है। 5 मैनडोनल्ड को पुन प्रधानमानी बनाने म राजा का प्रमुख हाथ था। उ होने ही बाल्डविन एव हवट सेमुअल को मक्डीनल्ड को प्रवानम नी बनाने क लिए तैयार किया था। मक्डोनल्ड को राजा के द्वारा चुना गया था। उस कोई दलीय सम थन नहीं था। सविधान शास्त्री कीय ने राजा के कदम के समयन म निम्न दो तक दिये हैं प्रथम देश के स्थणमान की रक्षा, तथा द्वितीय आगामी निर्वाचना म राष्ट्रीय सरकार का स्पष्ट बहुमत प्राप्त होना। लास्की के अनुसार प्रथम तक मा अय गई हुआ कि "राजा अपने निसी विचार के लिए बहुमत प्राप्त करन का प्रयस्न कर सकता है। यही जाज तृतीय की नीति थी। इसका स्वामाविक अथ यह है कि राजा तटस्य नहीं है।" यह संसदीय व्यवस्था का नियेव है। राजा नाममात्र का अध्यक्ष होता है। द्वितीय तक अपने आप मे ही जाघारहीन है। यह तो राजा के काम नो बाद म उचित ठहराना है। इसका अथ यह हुआ कि "राजा द्वारा निर्मित मित्रमण्डल यदि निर्वापना म बहुमत प्राप्त करन म सफल हाता ह ता राजा का बाय सबैधानिक हागा। नात्नी के अनुमार यह रातरनाक सिद्धा त है। ⁷

सिद्धा त में प्रधानम त्री जपन सहयोगिया को चुनन म स्वतात्र है परन्तु व्यव हार म उस अनक नियात्रणा के जधीन काय करना पढता है। दलीय हित के साथनाप

⁵⁵ Laski Parliamentary Government, p 235

⁵⁶ Lasks op cst, p 236

⁵⁷ Lasks op at, pp 405-407

देश के सभी औद्योगिक क्षेत्रा, वर्गी, हिता, घर्मा एव योग्य दलीय नेताजा को मित्रमण्डल म प्रतिनिधित्व देना आवश्यक होता है । इसके अतिरिक्त सभी मात्री ससद म स ही चुने जाने चाहिए। यदि नियुक्ति के समय कोई मात्री ससद का सदस्य नहीं होता तो 6 माह के मीतर उस ससद के लिए निवाचित हो जाना चाहिए। प्रधानम त्री लॉड नमा के सदस्या म मी कुछ सदस्या को मित्रमण्डल म शामिल वरता है। लाड सभा **ग अध्यक्ष—लॉड चा सलर्—अनिवायत म**ित्रमण्डल का सदस्य होता है। मित्रमण्डल के निर्माण म प्रधानम ती को योग्यता एव क्षमता दोना म समावय करना पडता है। लावेल के अनुसार प्रधानमात्री द्वारा मित्रमण्डल का निमाण विभिन्न प्रकार के असमान एवं विभिन्न सक्ताके टुकडा से किसी वस्तुके निर्माण के समान है।⁵⁸ लास्की ने निम्न शब्दा म बडे सुदर रूप म इस स्थिति की समीक्षा की है 'उसे अनेक परि-स्यितियों को ध्यान में रखना पडता है। दल के नेता के रूप में वह कुछेक साथिया की उपसा नहीं कर सकता नयाकि उनकी उपस्थित दलीय शासन के लिए अपेक्षित है। उसके नुछ साथी इतने महत्वपूण हो सकते हैं कि वे जिस विमाग का लेना चाह उह उसे वही विभाग देना पडता है। बास्तव में वह एक सावयवी इनाई का निमाण करता है जिसके सदस्य एक दूसरे के नायों के लिए सामृहिक उत्तरदायित्व वहन करने का तत्पर रहते है।"

"प्रधानमानी को राजा की भी स्वीकृति प्राप्त करनी पडती है। परम्परा के अनुमार निमुक्तिया के सम्बाध म विचार विमक्ष करना राजा का मौसिक अधिकार है। इस प्रकार राजा भी अपने विचारा से (मिनिमण्डल के निर्माण को) प्रभावित कर सकता है।"

"प्रधानमानी का विवेक एव प्रभाव निर्णायक हाता है। लेकिन विभागा कं वितरण कंसम्बाय म वह प्रमुख साथिया की उपक्षा नहीं कर सकता। उसे एक एसी टीम का निर्माण करना पडता है जो सफलतापूबक काय कर सके एव जो दल का सी स्वीकार हो।"

प्रधानमात्री की शक्तिया

प्रधानमा त्री ग्रेट ब्रिटेन एव उसके साम्राज्य का राजनीतिक सासक है। ब्रिटिश प्रधानन का प्रमुख है। रेमजे स्योर के अनुसार, "उसकी ब्रिक्तिया की विधिक व्याख्या प्राप्त नहीं है पर सु उसको जितनी व्यापक शक्तिया प्राप्त है उतकी विश्व के किसी नी

 ^{&#}x27;His work is like that of constructing a figure out of blocks which are too numerous for the purpose and which are not of shapes to fit perfectly together —Lowell The Government of England, Vol I, p 57 (Cited by Ogg & Zink Modern Foreign Governments 1956 p 85)
 Lask Parliamentary Government in England, pp 236 238

सबधानिक शासक, यहा तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति को भी प्राप्त नही है।" वह अत्यन्त व्यक्त व्यक्ति है। सम्पूण प्रशासन के लिए वह उत्तरदायी है।

- (1) वह मिनमण्डल का अध्यक्ष एव नेता है। विदिश सम्राट की सहमित स वह मिनमण्डल के सदस्यों को नियुक्त करता है। उन्हें वह पदच्युत भी कर सकता है। उनके मध्य विभागों का विवरण करता है। विभिन्न मनालया म उत्पन्न भव भेदों का समाधान एवं विभागों के कार्यों म समन्य करता है तथा उनकी कठिनाइयों को दूर करता है। सभी मनी उसमें परामद्र करते हैं। यित्रमण्डन की बैठका की अध्यक्षता करता है। वह इस बात पर इंटिंट रखता है कि सभी विभाग मिनमण्डत हारा स्वीकृत नीति का पासन करते हैं एवं स्वेच्छापूवक विभाग की नीति का निर्धारण नहीं करते। यिनमण्डल के निणया की निज्यान्वित करना उसी का दामित्व होता है।
- (2) प्रधानमानी को नियुक्ति सम्बन्धी ब्यापक सक्तिया प्राप्त हैं। राज्य एवं साझाज्य की सभी उच्च नियुक्तिया वास्तव म प्रधानमानी द्वारा ही की जाती हैं। राजबूती, मिन्मो तथा 1947 ई के पूब मारत के मवनर जनरक एव गवनरो आदि पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रधानमानी द्वारा ही की जाती है। वह साझातीय पुरक्षा समिति जसी समितियों की भी स्थापना करता है। युद्धकार में विभिन्न विमानों के कार्यों के मध्य समय पर स्थापित करने वालों सुरक्षा समिति का वह अध्यक्ष होता है। वह मिन्मच्यत्तीय सचिवालय पर निया पर स्थाप रखता है तथा समय समय पर उससे परासक एवं विचार विमया करता है।
- (3) प्रधानमानी कॉम स समा का नता कि शासन का प्रमुख अधिवक्ता होता है एव समस्त शासकीय मीतिया पर वह अधिकारपूर्वक निषय देता है। उसका विस्तिपण एव वक्तव्य सम्बन्धित विषय पर प्रामाणिक एव अतितम माना जाता है। काम समा का कायकम वही वियार करता है। वही यह निश्चय करता है कि सब के अधिवध्य कव और कितने समय के लिए बुलाये जाये। ससद का काय विवरण मी वहीं निश्चित करता है। शासकीय एव व्यक्तियत सस्य्या से सम्बन्धित कारों के लिए समय-विभाजन भी उसी की सहमित से किया जाता है। ससद के गुप्त अधिवेधन का समय भी वहीं निश्चित करता है। उसे वॉमम्स समा के विषटन की माय करत भी साक्ति भाष्त है। लॉड एव अय उपाधियों को देने के सम्बन्ध म भी सम्राट को बही अतिम रूप से परामध देता है।

(4) दश की विदेश नीति का वह प्रमुख निमाता है। वदशिक एव सम्पूर्ण

^{60 1942} ई तक प्रधानन भी कामन्त्र समा का नतुत्व करता था पर दु इस बप प्रधानम भी व नायभार को कम करन क लिए थी बार ए बटलर को नामत समा का नता बना दिया गया था। तब स यह प्रया चल पढी है कि प्रधानन भी एक काम स तमा क नता दो पृथक-पृथक व्यक्ति हो सवन है। परन्तु इसते प्रधान म भी क दानिस्वा म नाई नभी नहीं आती है।

अतर्रास्टीय प्रस्ता पर द्वासन का वह अधिकृत वक्ता होता है। यद्यपि वह विदेस मारी नहीं होता पर तु उसका विदेश नीति के निर्माण एव किया वयन पर निर्णायक प्रसाव हाता है। विदेश नीति सम्बाधी सभी महत्वपूण घोषणाएँ प्रधानमानी द्वारा ही की जाती है। विदेश मारी द्वारा कोई निर्णय करने में पूब प्रधानमानी सा परामश्च किया जाता है। यह मी सम्मव है कि विना मानिमण्डल के विचार विमश्च के करता है वह प्रशान माने के परामश्च है कि विना मानिमण्डल के विचार विमश्च के कर प्रधान माने के परामश्च है कि विदेश मानी कोई काथ कर सकता है। अर एडवड थे ने 30 सुताई, 1914 ई की विदिश तटस्थता विपयक तार प्रधानमानी एडिवड के परामश्च है हो सेवा था। 1914 ई में जमनी को जल्दीमेटम मानिमण्डल के विचार विमश के प्रवानमानी की सहमति से ही सेवा भाग था। प्रधानमानी का विदेश मानी सेविद्य तटस्थता के विपानमानि के निर्मात के सिक्ता के स्वान स्वान है। अपनामानी विद्या तटस्थता थे। वे स्वय ही म्यूनिल वेष्ट के निर्मा उत्तरदायी थे। स्वेज सकट (1956 ई) के लिए प्रधानमानी ए थानी इंडन उत्तरदायी थे। श्री चिंकत दितीय विद्या नीति के निर्माणक थे। विदेश के राजदूता वा प्रधानमानी स्वार स्वान विद्या नीति के निर्माणक थे। विदेश के राजदूता वा प्रधानमानी हिस समित है।

(5) प्रधानमंत्री मित्रमण्डल एव राजा के मध्य कढी का काय करता है।
सित एव राजा के मध्य सभी पत-ध्यवहार उसके माध्यम से होता है। उपनिवेशा के
प्रधानमत्त्रिया से उसका सीधा सम्पन्न होता है। सम्राट एव मित्रमण्डल के मध्य
कडी के रूप मे प्रधानमंत्री महत्वपूण भूमिका निमाता है। यह मित्रमण्डल के निणयो
स सम्राट को भूषित करता है एव सम्राट की स्वीकृति प्राप्त करता है। सम्राट को
प्रधानमंत्री द्वारा विमिन्न मित्रया के विचारों को बताना आवश्यक नहीं है। परतु
स नियम के मुख अपवाद भी है। उदाहरणाब्द, प्रधानमंत्री डिजरेती साम्राशी
विकटीरिया को मित्रमण्डल म होन वाले विचार विमश्च को विस्तृत भूवना विया करते
थ। परतु यह रीति जिचत नहीं है। इससे सम्राट के ह्वय म उस मंत्री के
प्रति संबह उरप्त हो सकता है जिसके विचार उनके विचारों के अधिक निकट
नहीं होत है। सम्राट के हृदय मे सभी मित्रया के लिए समान सद्भाग रहना चाहिए।
कत यह आवस्यक है कि प्रधानमंत्री सम्राट को मित्रमण्डल को वैक्त का ना विवरण
म द। यदि वह ऐसा करता है जो एक प्रकार से वह जपने सहयोगी मित्रमों के प्रति
विन्नसंस्रात का दोपी समयन जा सकता है।

(6) वह दस का प्रमुख नेवा एव समदीय दल का प्रमुख होता है। सम्र में अपने दत एव विरोधी दल के सदस्यों से निर तर सम्पर्क रखता है। वह दल की किया प्रमुख होता है। वह दल की रहता समितिया एवं समठनों का प्रमुख होता है। दलीय प्रचार मं वह पूण सिन्य रहता है।

प्रधानम त्री की स्थिति

प्रधानमात्री देश का यथाय शासक है। फाइनर के अनुसार प्रधानमात्री की

प्रमुखता के कारण मिनमण्डल की अध्यक्षता, ससद का नेतृत्व, सम्राट के साथ व्यवहार म प्रमुख कठी की स्थिति एव उसका प्रमुख दक्षीय नेता होना आदि हैं। वह सर्वोच्च राजनीतिक श्रक्तिक का मूर्तिमान रूप है। वैशे देश मे होने वाले सामाय निर्वाचन वास्तव मे प्रधानमा नी के निवाचन होते है। व्य 1880 ई के निर्वाचनो में गर्वेडरदोन ने डिजरायली के प्रशामन की तीव आलोचना की थी। अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता के परिणामस्त्वरूप हो ग्वेडस्टोन 1880 ई मे विजयी हुए थे। 1945 ई के निर्वाचनो में प्रधानमा नी चिंचल ने मतदाताओं से व्यक्तिगत रूप म अपने दल को विजयी बनावें की अपील की थी। स्मरणीय है कि 1945 ई म अमुदार दल ने कोई चुनाव घोषणा पन जारी नहीं किया था, अपितु प्रधानमानी चिंचल ने व्यक्तिगत रूप म एक घोषणा पन जारी नहीं किया था। अनुदार दलीय उस्मीदवारों ने अपने को चिंचल का प्रत्यापी घोषित किया था। अनुवार प्रजीय उस्मीदवारों ने अपने को चिंचल का प्रत्यापी घोषित किया था। चुनाय प्रचार के मैदान म 'विचल बनाम लास्की', 'विचल या विनार्ष' आदि नारे लाग्ये गरे ये

जैनिस्स के अनुसार, 'प्रधानम'तो केवल समकक्षो स प्रथम नही है, न वह जसा हरकोर्टन कहा है, तारा के सध्य चंद्रमा है। अपितु वह सूय है जिसके चारी तरफ अप्यनक्षत्र प्रमते हैं। ⁶⁸

विरिशं प्रधानमानी के सदम में लास्की का तिम्म क्या महत्वपूण है "प्रधानमानी वह धुरी है जिसके चारा तरफ सम्मूण शासनतान प्रमृता है। वह काय पातिका के प्रमावदाती भाग का अध्यक्ष है। वह विभागों के मध्य मतनेश्वा को दूर करता है, राजा की अनुमति से किसी भी मानी स्वापण्य माग सकता है, तथा महत्वपूण निमुक्तिया के सदम म उसका मत निर्णायक होता है। यह सभी विमाग, विरावस्य विदेश विमाग पर दृष्टि रसता है एवं नीति के समावयक्तों के रूप म काय करता है। वह काम स सका करता है। वह काम स समा का नेता होता है एवं सामा य सदस्या द्वारा किनाई स ही सामाय मानी के निणय के अतिरिक्त अपील की जाती है। वह सम्राट एवं मित्रमध्य के मध्य प्रमावकारी कड़ी है। विधि हैं। उपरोक्त क्या प्रमावकारी कड़ी है। विधि हैं। उपरोक्त क्या क्या य उसवे या द ही विधि हैं। उपरोक्त क्या क्या का अध्यक्ष विद्या है। तथि हैं। उपरोक्त क्या क्या का अध्यक्ष विभाव होता है जब तक उसन अपन कार्यों म (अपन विरद्ध) व्यापक वस तोय उत्पन्त कर तिया हो। ध

नि अपने काया में (अपने विस्दे) व्यापने असे तीप उत्पन्न कर लिया हो। प्रधानमंत्री का पद उसका धारण करने वाले ने व्यक्तित्व पर निमर परती

⁶¹ Finer Theory & Practice of Modern Government, pp 592 93

^{61 **}Rier Inter of Fractice of Mooren Government, pp. 322.

"A General Election is, in reality, the electron of Frime Minuter
The elector has a choice between Gladstone and Disrach
Salisbury and Rosebery, Balfour and Campbell Bannermann
Asquith and Balfour Mcdonald and Henderson, Churchill
and Attlee —Jennings The British Constitution, p. 162

⁶³ Jennings Cabinet Government, pp 183 184

⁴ Lasks Parliamentary Government in England, pp 239-41

। लॉर्ड सलिसबरी अपने मि त्रमण्डल के सदस्यो पर भली प्रकार नियातणा भी नही र सक ये। लॉड रोजवरी की भी यही स्थिति थी पर तु डिजरायली, ग्लेडस्टोन एव र्जिल की सत्ता को उनके सहयोगियों में से कोई चुनौती देने वाला नहीं था। प्रधान त्री की योग्यता, जानकारी का व्यापक क्षेत्र, अध्यक्ष के रूप मे उसकी योग्यता, तीघ्र कार्य एव निणय करने की क्षमता, पूण महत्व एव महत्वहीन कार्यो मे अ तर करने की ग्रक्ति आदि का उसके पद, शक्ति एव प्रमाय पर व्यापक प्रमाय पडता है। युद्ध-काल म उसकी राक्ति का क्षेत्र आश्चयजनक रूप में अत्यधिक बढ जाता है। आधुनिक काल म शासन के कायक्षेत्र मे वद्धि के कारण प्रधानमात्री केवल नीति सम्बाधी सामाय रूप रखा ही निर्धारित कर पाता है। पर तु लास्की के मतानुसार इससे प्रधानम नी की ग्रीक्त से कमी नहीं आयी है। ⁶⁵ सामा य निर्वाचनों में प्रधानम ती को राष्ट्रीय आधार प्राप्त हो जाता है और जब तक वह प्रधानम नी है कोई उसको चुनौती नहीं दे सकता। 'दल उसके व्यक्तित्व पर आधारित होता है और जब तक दल पर उसका पूर्ण नियानण हाता है कोई उसका विरोध नहीं कर सकता। 100

प्रधानम री की स्थिति इतनी महत्वपूण होने पर मी, फाइनर⁸⁷ के शब्दा म, "वह सीजर नही है। वह ऐसा देवता नहीं है जिसे चुनौती नहीं दी जा सके। उसके विचार आदेशा के सहश्य नहीं होते हैं। वह सदैव इस दया पर निमर रहता है कि उसके द्वारा निश्चित ही लाभदायक सेवा की जा रही है या नहीं। किसी भी क्षण उसको कोई विरोधी अपदस्य कर सकता है।" आधुनिक काल मे उसकी सत्ता म असा पारण वृद्धि हुई है। प्रो चेस (Prof Chase) का कथन है कि आधृतिक वर्षा म प्रधान-म तो की स्थिति अद्ध अध्यक्षात्मक (Quasi Presidential) हो ययी है। इसका अप है कि प्रत्यक्ष रीति से निवाचित होने के कारण वह अपने (मित्रमण्डल के) सदस्यो एव सपद से स्वतान अपने पद का उपमीग करता है। लेकिन प्रो सास्की इस मत की स्वीकार नहीं करते । उनके अनुसार यह कहना उचित नहीं है कि "ब्रिटिस प्रधानम त्री की स्पिति अमेरिकी राष्ट्रपति के समान है। दलीय सगठन के परिपेक्ष्य में उसकी स्थिति प्रमावपूर्ण है। मुनिध्वत रूप मे प्रदत्त विधिया उसकी विक्ति का आधार मही है। लेकिन में समफता हूँ कि मिन्सण्डल पर जितना अधिक प्रधानमानी का निय नण होता है उतना ही अधिक ससदीय प्रणाली के सक्लतापूर्वक चलने की आधा

⁶⁵ Lasks op cst, pp 239 41

The Prime Minister is not a Caesar He is not an unchalleng 66 Ihid able oracle, his views are not dooms, he malways on sufferance, 67 useful service its terms are whether he can reader indubitably useful service At any time a rival may supplant him "—Finer op at, p 581

⁶⁸ Laski op cit, p 241

होती है।" प्रधानमात्री की स्थिति के सादम में निम्न बाता को सदैव ध्यान म रखना

चाहिए प्रधानम नी की स्थिति, शक्ति, प्रभाव एवं शासनत न म स्थान उसके

व्यक्तित्व एव साथियों के साथ उसके सम्बाधी पर निर्मर करता है। एस्निवय, नायह जॉज एव चर्चिल की स्थिति प्रधानमात्री की विधिक शक्तियों की अपेक्षा उनके

व्यक्तित्व एव दल मे उनके असदिग्ध एकाधिकारी नेतृत्व पर निमर थी। (2) प्रधानमात्री को यदि दल के बहमत का समयन प्राप्त नहीं है ता उसके

लिए प्रधानमन्त्री रहना असम्भव है। जत उसे सर्देव जनता की नाडी पर अपना हार रत्वते हुए दल की आवश्यकताओं के प्रति पूज सजग रहना चाहिए।

ब्रिटिश प्रधानमानी, बेजहोट के अनुसार, शासन विधान के सफल एव कुशत अग का प्रधान है। सिखनी लो के अनुसार, "वह जमन सम्राट तथा अमेरिकी राष्ट्र पति एव सयुक्त राज्य की काग्रेस की सिमितियों के समापतियों से भी अधिक शक्ति

शाली होता है। 'वैधानिक शासका म वह विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक है।

19

फ्रास, जर्मनी एव सोवियत रूस की कार्यपालिका [EXECUTIVES OF FRANCE, GERMANY & SOVIET RUSSIA]

इस अध्याय मे महाद्वीपीय देशा--फास (तृतीय, चतुय एव पचम गणराज्य), जयनी एव सीवियत रूस (स्टालिन सविधान) की कायपालिकाओ के स्वरूप एव प्रकृति का विश्लेषण किया गया है।

फ्रान्सोसी कार्यपालिका [FRENCH EXECUTIVE]

फान्स को सबैधानिक प्रयोगा की प्रयोगशाला की सज्ञा दी जाती है। फान्स की वतमान शासन व्यवस्था एव उससे सम्बधित समस्याथा की समभने के लिए फारस के सबधानिक विकास पर हण्टि डालना हितकर होगा। निरनुश राजत व स सावि-धानिक शासन के विभिन्न अनुसवी के पश्चात ही फास म ससदीय शासन की स्थापना सम्मव हुई थी । दूसरे शब्दा म निरक्शत न से सवग्रक्तिमान व्यवस्थापिका एव कायपालिका की तानाशाही के अनुभवों के पश्चात ही संसदीय शासन की स्थापना हुई थी। 1789 ई की राज्यकान्ति के पश्चात निर्मित 1791 ई के सुविधान के अधीन निरकश बोरवन-वशीय राजतात्र को सीमित राजतात्र म परिवर्तित कर दिया गया था। राजा को विधि निर्माण एव व्यवस्थापिका को मग करने की कोई शक्ति प्राप्त मही थी। माप्रीमण सिद्धा तत राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे लेकिन उन पर उच्च यायालय म अभियोग भी लगाया जा सकता था । विधि निर्माण, करारोपण, युद्ध की घोषणा एव शान्ति सम्बाधी अधिकार व्यवस्थापिका को प्राप्त थे। व्यवस्थापिका एक-सदनीय थी। दो वप के लिए इसके 745 सदस्य प्रत्यक्ष कर देन वाले मतदाताओं द्वारा सीमित मात्रा म चून जाते थे । ऱ्यायाधीश निर्वाचित होते थे । स्थानीय शासन लोकत त्रीप सिद्धात पर पून संगठित किया गया था। यह सविधान बहुत समय तक सन्तोप रूप म न चन सका । लुई जठारहवे वी कमजारी एव अस्पिरता ने इस सविधान के सचालन सम्बामी कठिनाइयाँ बढा दी थी । व्यवस्थापिका सभा न लुई सालहर्वे को



लेकिन प्रथम गाउ सल वास्तविक सत्ता का उपमोग करता था। व्यवस्थापिका मे सीनेट सर्वोच्च थी एव किसी भी विधेयक को वह असवधानिक घोषित कर सकती थी । सीनेट एक मनोनीत सदन था । व्यवहार में प्रथम काउ सल की इच्छा ही अतिम होती थी। 1804 ई. म नेपोलियन न सम्राट की उपाधि धारण की। 1815 इ. मे नेपोलियन की पराजय के बाद फास म बोरवन वश की स्थापना हुई और 15 वर्षों तक फास म निरकुरा राजत नीय शासन चलता रहा। 1930 ई में द्वितीय काति हुई। लुई फिलिप को सिहासनारूढ किया गया तथा उसे सीमित शक्तियाँ प्रदान की गयी। . फास म इसके साथ सीमित राजत त्र की स्थापना हुई। मध्यम वग को मताधिकार प्रदान किये गये। राजाफेचवासियाका राजाधान कि फास का । सन्तियो को एक सीमा तक व्यवस्थापिका समा के प्रति उत्तरदायी ठहराया गया। व्यवस्थापिका को विधि निर्माण सम्ब धी व्यापक शक्तिया प्रदान की गयी। लुई फिलिप के शासन को 'नागरिक राजत न' (Cruzen Monarchy) की सज्ञा दी जाती है।

दितीय फ्रेंच गुणराज्य (1848 1852 ई)

1848 ई की फ्रेच जाति के फलस्वरूप दिलीय फ्रेच गणराज्य का जम हुआ था। यह गणराज्य अल्पकालीन था। 1852 ई मे फास प्रशा युद्ध के कारण इसका पतन हो गया । द्वितीय फेच गणत नीय सविधान ने ससदीय शासन की स्यापना की थी । इसका निर्माण सविधान समा द्वारा किया गया था । ससदीय शासन-ब्यवस्था केवल नाममान की थी। ब्यवस्थापिका एकसदनीय थी। इसके 750 सदस्य तीन वप के लिए प्रत्यक्ष रीति से 21 वप या उससे अधिक जायु के पुरुष नागरिको हारा चुने जाते थे। कायपालिका शक्ति राष्ट्रपति मे अधिष्ठित थी जो चार वप के लिए प्रत्यक्षत जनता द्वारा चुना जाता या । राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मानीगण असेम्बली के प्रति उत्तरदायी होते थे। असेम्बली को राष्ट्रपति भग नहीं कर सकता था। राष्ट्रपति को विधिया प्रस्तावित करने का अधिकार था। प्रत्यक्ष रीति से जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति के समक्ष असेम्बली की स्थिति गौण हो गयी थी। लुई नेपोलियन जसे प्रमावद्याली व्यक्तित्व को राष्ट्रपति चुना गया था। 1852 ई म सनिक नाति द्वारा लुई नपोलियन ने अधिनायकत नीय शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी, फलस्वरूप मित्रया को राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया और राष्ट्रपति का कायकाल 10 वप निश्चित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त लुई नेपोलियन ने अपने को सम्राट भी घोषित कर दिया था। उसने नेपोलियन बोनापाट के समय की काउ सलेट की माति के सविधान को लागू किया लेकिन जन विरोध के कारण सम्राट को उदार नीतिया का अनुगमन करना पडा। इसकी चरम परिणति मई 1870 ई के सविधान में हुई। इस सविधान के अत्तगत म त्रीगण जो दोना सदना के सदस्य होत थे व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी ठहराये गरे। सम्राट मित्र परिषद (Council of Ministers) की अध्यक्षता करता था। व्यवस्थापिका के दोना सदना एव नाय-

पालिका को विधियाँ प्रस्तावित करने के अधिकार प्राप्त थे। यथाथ म इस सविधान द्वारा साम्राज्ञीय प्रणाली एव ससदीय प्रणाली म समावय स्थापित करने का प्रयत किया गया था, लेकिन इस सविधान को स्वीकार करने के 4 माह के भीतर ही द्वितीय साम्राज्य का अत हो गया।

वृतीय फ्रेंच गणराज्य (1870 1940 ई)

1870 ई मे ततीय गणराज्य की घोषणा की गयी । इसके सविधान के निर्माण म आगामी 5 वय लगे थे। ततीय फ्रेंच गणराज्य का सविधान फरवरी 24, फरवरी 25 एव जुलाई 16, 1875 हैं की तीन विधिया म पाया जाता है। इसम कुल 24 अनुच्छेद है। इस सविधान की कुछ प्रमुख विश्लेषताएँ निम्नवत हैं

(1) एकारमक शासन की स्थापना की गयी एव समस्न शक्तियाँ के द्रीय सर

कार में अधिकित की गरी थी।

(2) फास को गणराज्य घोषित किया गया और सबैधानिक सशोधन द्वारा इस व्यवस्था में परिवतन निधिद्ध कर दिया गया था।

(3) सविधान कठोर था। फेंच ससद द्वारा साधारण विधि पारित करने नी प्रित्या द्वारा इसम इसम सरोधन सम्भव नही था । सविधान म सद्योधन दोनो सदनो द्वारा पृथक पृथक रूप म स्पष्ट बहुमत से पारित किय जाने के पश्चात पुन दोना सदना के समुक्त अधिवेशन (राष्ट्रीय समा) द्वारा स्पष्ट वहमत से पारित होने पर हां प्रमानकारी होता था । सविधान की कठोरता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 1875 ई से 1940 ई तक केवल तीन सशोधन किये जा सके थे।

(4) तृतीय गणत त्रीय सविधान के द्वारा नमदीय शासन की स्थापना की गमी और कायपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी ठहराया गया था। फ्रेंच राष्ट्रपति बिटिश सम्राट की मौति नाममान का अध्यक्ष था । मनि परिपद वयाय

कायपालिका थी।

(5) फेच ससद म दो सदन थे (1) चेम्बर ऑफ डिप्टीज, एव (11) सीनट। विम्बर ऑफ डिप्टीज के 618 सदस्य चार वय के निए सावमीम वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होते थे। सीनेट के 314 सदस्य नौ वय के लिए चुने जाते ने एव एक तिहाई सदस्य प्रति तीन वय बाद अवकाश ग्रहण कर सते थे।

ततीय गणराज्य का पतन जुलाई 1940 ई म हो गया । इस दिन विची (Vichy) म चेम्बर ऑफ डिप्टीज एव सीनेट ने जपने सयुक्त अधिवेशन बर्बात राष्ट्रीय समा के रूप म एक प्रस्ताव पारित किया। इसके द्वारा राष्ट्रीय समा ने माधल पेता के नतत्व मे गणराज्यीय शासन को फेच राज्य के लिए एक या अधिक अधिनियमी द्वारा नवीन सर्विधान बनाने ना अधिकार प्रदान किया। दूसरे दिन भाशन पता ने राष्ट्रपति सम्ब भी सभी सबधानिक व्यवस्थाओं को निलम्बित करते हुए स्वय की राष्ट्रपति घोषित कर दिया। च होने मित्रया को नियुक्त एव पदस्युत करने की

शक्तियां भी अपने हाथो म ने ली । व्यवस्थापिका के अधिवेशन सम्बाधी समस्त सबै धानिक व्यवस्थाओं को भी समाप्त कर दिया। राष्ट्र विरोधी कार्यों के लिए चैम्बर ऑफ डिप्टीज द्वारा राष्ट्रपति एव मनिया पर अभियोग लगाने की शक्ति को भी समाप्त कर दिया गया। पेता फास का अधिनायक बन बैठा। अगस्त 1940 ई म माश्चल पेता जमनी चला गया । कुछ समय तक यह कठपुतली सरकार सत्तारूढ वनी रही । मादाल पेता के विची शासन के विरुद्ध जनरल डिगाल के नेतृत्व मे फेच स्वात य सघप प्रारम्भ हुआ । सितम्बर 1941 ई मे स्वतान फ्रेच राष्ट्रीय ममिति (Free French National Committee) की स्थापना की गयी । इसने 'स्वत न फास' के नाम पर सचय जारी रखा। अल्जियस म सितम्बर 1943 ई. मे 84 सदस्यी फेच परामशदायी समा (Consultative Assembly) का निर्माण किया गया। जून 1944 ई मे फेच राष्ट्रीय समिति ने अपना नाम फेंच गणराज्य की अस्यायी सरकार मे बदल लिया। 25 अगस्त, 1944 ई को फास म जमन सनिको ने आत्मसमपण कर दिया एव जनरल डिगाल के नेतृत्व मे अस्थायी शासन की स्थापना की गयी। प्रथम 14 महीनो मे परामशदायी सभा के होते हुए भी जनरल डिगाल ने मित्रयो का खद ही चुनाव किया था और वे केवल उनके प्रति ही उत्तरदायी थे। स्वतानता के पदचात के इन 14 महीना के शासन को 'सहमति से अधिनायकत न' (Dictatorship by Consent) की सज्ञा दी गयी थी।

हितीय युद्धोत्तरकालीन फास के नव सविधान के निर्माण हेतु जून 1946 ई म नवीन सविधान समा का चुनाव हुआ था। नवीन सविधान को सविधान समा ने 13 अब्दूबर, 1946 ई को स्वीकार किया एव 27 अब्दूबर 1946 ई से वह लागू हुना। यह फास के चतुष गणराज्य का सविधान था जो 1958 ई तक चलता रहा। 1958 ई में फास के पाचवें गणराज्य का उदय हुआ।

फ्रासीसी मन्त्रिमण्डल

फास के ततीय एव चतुष गणराज्य के अत्तगत कायपालिका शक्ति राष्ट्रपति एव मी नमण्डल मे निहित थी। राष्ट्रपति नाममात्र का अध्यक्ष या और मीजमण्डल यथाय कायपालिका थी।

हतीय गणराज्य के अत्तमत प्रधानमंत्री कायपालिका का बास्तविक अध्यक्ष हुआ करता था। वह मित्रमण्डल का भी अध्यक्ष था। मित्रयो के लिए ध्यवस्थापिका के कियी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं था, लेकिन ध्यवहार प डिप्टीज एव सीनेटरों में से ही मानी चून जाते थे। मित्रमण्डल की सदस्य सस्था सविधान द्वारा निश्चित नहीं थी। ततीय गणराज्य के अत्यग्त मित्रमण्डल या प्रधानमंत्री को चेत्रमण्डल नहीं थी। ततीय गणराज्य के अत्यग्त मित्रमण्डल या प्रधानमंत्री को चेत्रमण्डल को मांग करनं का अधिकार प्राप्त पा। इस अधिकार का केवल एक बार थकमाहन सकट (जून 1877 हूं) के समय ही प्रयोग किया गया था।

534 | आयुनिक शासनत त्र

तृतीय फेच गणराज्य की मी त्रमण्डलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ निम्न वत थी

(1) फेंच मिनिमण्डल अल्पकालीन रहे थे । इसका बारण बहुदलीय पदाति थी। समुक्त मिनिमण्डल अल्पकालीन रहे थे । इसका बारण बहुदलीय पदाति थी। समुक्त मिनिमण्डल अपनी प्रवित्त में ही अस्थिर होते हैं। फाइनर के अनुसार "फास म अनेक (राजनीतिक) समूह थे। यदि व्यवस्थापिका में किसी नेता के हाथ म 10 या 15 मत होते थे तो वह शासन के लिए सानाशाह वन सकता था। 1924-28 ई को सस्ट में 10 विभिन्न (राजनीतिक) समूह या गुप एवं 31 निदलीय सदस्य थे तथा 1932 ई में 16 पूर एवं 26 निदंशीय सदस्य थे। किसी दल को निम्म सदन—चेश्वर आफ डिट्रीज—में कमी स्थवर बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था अत हर सरकार संगुक्त सरकार होती थी।" 1875 से 1925 ई तक फास म 50 मिनिमण्डकों का निर्माण हुआ वबिक इसलेष्ट में इसी काम में केवल 12 मिनिमण्डक वने थे। अत स्पट है कि समुक मिनिमण्डलों का कायकाल अति अल्य हुआ करता था। फाइनर के अनुसार 1873 से 1940 ई के बीच फास में 100 मिनिमण्डल वने थे। बत स्पट है कि समुक मिनिमण्डलों का कायकाल अति अल्य हुआ करता था। फाइनर के अनुसार 1873 से 1940 ई के बीच फास में 100 मिनिमण्डल वने थे बिनका औरत कायकाल केवल 8 माह से कुछ ही अधिक था। इनमें से कुछ मिनिमण्डल तो एक सप्ताह से भी कम समय के लिए पदाच्च रह सके थे। फास में मिनिमण्डलों ये कामकाल को कामकाल अति प्रकृत सार से प्रविच्या को मती प्रकार अनुमान तो हमें तलीय गणराज्य के चार दीघकालीन मिनिमण्डलों के कामकाल की सामकार की विच्या सामीकार से ही नात हो सकता है। बाल्डक रहती (3 वप), कोम्बर (2 व्या तथा मतीने सा (दो वार 3 3 वप) के मिनिमण्डल कुल मिलाकर केवल 11 वप तक सत्ताख्य रहे थे। ये वार से दिमालकर कुल मिलाकर केवल 11 वप तक सत्ताख्य रहे थे। है से प्रवास स्वासार के वर ही थे।

(2) इगलैण्ड मं एक मित्रमण्डल के त्यायपत्र के परचात नवीम मित्रमण्डल के निमाण के साथ प्राय नय मंत्री पदास्त्र होते हैं। फांच मे ऐसी स्थित नहीं है। फंच मित्रमण्डल मे परिवतन का अब केवल ताल के पत्ता का फोटना न होकर उनका बदला हुआ करता था। पदत्याग करने वाले मित्रमण्डल के अनेक सदस्य सामायत गर्य मित्रमण्डल म पद ग्रहण करते थे। अक्टूबर 1933 ई म डालेदियर मित्रमण्डल के एक पदस्य Sarnanst न नवीन मित्रमण्डल का पत्त के पदस्य Sarnanst न नवीन मित्रमण्डल काचा या। इस नये मित्रमण्डल म 18 मे से 12 सदस्य पुरान मित्रमण्डल के थे। इनलडम इसकी कल्पना मी नही की जा सकती। इस प्रकार की कायवाही को Replastern8 कहा जाता है। कनी कमी इस Dosage अथवा Dosing अर्थात मरणासन्न रागी की हुस नये मित्रमण्ड कर य औषधि देना भी कहा जाता है।

(3) व्यक्तिगत रूप म मित्रयो द्वारा आये दिन त्यागपत्र दिय जाते थ । इस

¹ Finer op cit, p 625

² Ibid p 627

प्रकार के त्यागपत्र मी तिमण्डल की हिन्द से बहुत हानिकारक होते थे। इनके कारण मित्रमण्डल शक्तिशाली होने की अपेक्षा कमजोर हो जाता या तथा अनेक मित्रमण्डलो कापतन हो गयाथा।

- (4) तृतीय गणराज्य की मित्रमण्डलीय कार्यपालिका की अय महत्वपूण निशेपता उसका अत्यधिक शक्तिहीन होना था । फ्रेंच प्रधानमात्री ब्रिटिश प्रधानम ती की माति शक्तिशाली नही था। जिटिश प्रधानम ती ऐसे मित्रमण्डल का प्रमुख एव नेता होता है जो दलीय अनुशासन के कारण एकता के सुन्न मे आबद्ध रहता है। फैच प्रधानमानी मित्रमण्डल के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता या। वह व्यवस्थापिका की ययाशक्ति नियन्तित करता तथा मन्त्रिमण्डल को एक सूत्र म आबद्ध रखता था। वह देश मे अपनी लोकप्रियता को कायम रखने के लिए अथक प्रयत्नशील रहता था। ब्रिटिश प्रधानमात्री की माति कींच प्रधानमात्री को चेम्बर ऑफ डिप्टीज को विषटित करने की शक्ति प्राप्त नहीं थी। अधिकाश मात्री अपने व्यक्तिगत प्रमाव के कारण चुने जाते थे। फास ने दलीय अनुशासन नाममान का है। अधिकतर संयुक्त मित्रमण्डला का ही निर्माण होता रहता या । प्रधानमात्री को केवल अपने दल का ही नेतत्व नहीं करना पडता था अपित उसे अन्य दलों को भी साथ म लेकर चलना पडता या । फाइनर के अनुसार व्यवहारत प्रधानमानी का वहत सा समय सम्प्रभुता प्राप्त करने म व्यतीत हो जाता था जिससे कि मिनमण्डल को जीवित रखा जा सक ।3 1873 से 1940 ई तक ऐस केवल चार प्रधानमात्री हुए थे जिनका कायकाल 4 वप स अधिक था जबकि सनह प्रधानमिनयो का तो कायकाल 6 माह से भी कम था। 1928 से 1940 ई तक कुल पद्रह प्रधानमात्री हुए ये जिनम संस्तात का कायकाल 6 माह से भी कम था। केवल एक प्रधानमात्री का कायकास करीब 2 वप स कुछ कम था।
- (5) फाइनर के अनुसार बहुत कम व्यक्ति दीघकाल तक किसी विमाण क मात्री रह पात थे, फलस्वरूप व न ता अपनी याग्यता की छाप छाडत थ और न विमाग सम्बंधी कार्यों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्ह पयाप्त समय ही प्राप्त हाता था । परिणामस्वरूप ने दीधनासीन नीतियाँ त्रिया नित नहीं कर पात थे । उनरा अधि-बास समय ससद और आयोगा के सदस्या एव प्रतिनिधि मण्डला स मिलन में निरस जाता या। हर नय मित्रमण्डल म पुराने मित्रमण्डल व बुद्ध मदस्या क हान पर मी यह आवश्यक नही था कि उन्ह बही विमाग दिय जायें जा उनक पान पहल थ । यदि विमान म परिवतन नहीं होता था ता भी उस नय सहयानिया एवं नय प्रपानमंत्री न साथ सवया नवीन एव संयुक्त संसदीय कायकम के अधीन काय करना पढता था। पात्र म 1873 स 1940 इ. तक 27 विदश्चमात्री 37 गहमात्री, 38 विसमात्री

³ Finer op at, p 628 4 Ibid, pp 628 629

एवं 42 कृषिमात्री हुए थं। इस प्रकार मत्रिया ने विज्ञामा में तीत्र गति में परिवतन ने फलस्वरूप शासन में स्थापित्व एवं सुदीपनात्तीन नीति एवं नायत्रमा का क्रिया वयन न हो सनना स्वामावित ही था।

- (6) फाइनर के अनुसार, "मित्रमण्डल के लिए सीनट एक अतिरिक्त करिनाई का पारण थी।" फेंच मित्रमण्डल दाना सदना—चेम्बर ऑफ ढिस्टीज एव सीनट—के प्रति उत्तरदायी होता था। इगलण्ड म मित्रमण्डल केवल निम्म सदन—कामल समा—क प्रति ही उत्तरदायी होता है, उच्च सदन—लॉर्डसमा—वे प्रति नही। इसके विचरीत, ततीय फेंच गणराज्य के अत्याल सीनेट के विचरीत मत क पलस्वस्य फेंच मित्रमण्डला का चतन हो जाता था। बोगींस मित्रमण्डल (1896 ई), विची का मित्रमण्डल (1913 ई), हेरिया मित्रमण्डल (1925 ई), टारडीन मेन्त्रमण्डल (1930 ई), लावेल मित्रमण्डल (1932 ई) एव ब्लूम (Blum) मित्रमण्डल (1937 ई एव 1938 ई) का पतन सीनट के विचरीत यत का परिणाम था। अत्र प्रत्येक मित्रमण्डल स सीनेट म स कुछ सदस्य अनिवायत लिय जात हैं। 1873 ई से 1940 ई तक 54 प्रधानमित्रमा म स 22 प्रधानमित्री सीनट के सदस्य थे।
- (7) राष्ट्रीय समा के सदस्या को मित्रमण्डल स प्रस्त पूछन एव सूचना प्राप्त करन के व्यापक अधिकार प्राप्त थे। प्रस्त इतनी चतुराई स पूछे जात थ कि विमानीय मित्रमा को अधिकाशत बदनामी ही पल्ले पढती थी। बाद-विवाद को सीमित करने का मित्रमण्डल को कोई अधिकार नहीं था। बाद विवाद क पश्चात यदि अविद्याल का प्रस्ताव पारित हो जाता था तो मित्रमण्डल का त्यापपन देना पडता था। वेस्पर ऑफ डिट्टीज हारा केवल सामाय नीति के सम्यप म ही नहीं अधितु प्रशासन के सम्यप म भी छानबीन की जाती थी। मित्रमा के साथ एक किं नाई यह थी कि अस्थायी मित्रमण्डलों के कारण उनके समयका का अमाव होता था।
- (8) फास म असम्बली द्वारा नियुक्त आयोग विधि निर्माण, विसीय एवं प्रशासकीय कार्यो म महत्वपूण भूमिका निमाति है। इन आयोगो म भूतपूव मंत्री तथा सीनेट और चेम्बर ऑफ डिप्टीज के अनुमवी एवं प्रमावदात्ती सदस्य होते हैं। इन आयोगो के अस्तित्व के कारण मिनमण्डल की स्थित कमजोर हो गयी है। फाइनर के अनुसार, "यह आयोग मिनमण्डल को नमजोर बनाते हैं। यह मित्रयों के तीज प्रतिस्था है और चेम्बर सदन मिनमण्डल की अपेक्षा आयोगो से मायदान की अधिक अपेक्षा करता था। इसके विपरीत, इयलण्ड म मिनमण्डल ही मायदान को सोत होता है।" आयोगो को विमाता से सुनना प्राप्त करने के मी अधिकार होते हैं एवं इस प्रकार सुचनाएँ प्राप्त करके वे मिनया के पतन का माम प्रवस्त कर दते हैं। इसरी आर, म नीमण दोपयुक्त योजनाओं और सीमित एवं अनुपयुक्त प्रशासन के लिए

⁵ Finer op cit, pp 628 629



राष्ट्रीय समा म साम्यवादी दल न सन्स्य मतदान म माग नहीं सगे। सिर्म इस निणय में विपरीत मित्रमण्डल न साम्यवादी मात्री बठका म नाम लेत रहे और राष्ट्रीय समा म सास्यत नी नीतिया न पक्ष म जहान मतदान मी किया। बाद म मित्रया सहित समी साम्यवादिया न राष्ट्रीय समा म मित्रमण्डल द्वारा स्थोहत वेतन नीति (Wage Policy) में बिरुद्ध मत दिया लिहन साम्यवाने मित्रया ने मित्रया ने सिर्म पर्वे कर ने पर्वे कर दिया। साम्यवादी मित्रया के दस नाय वे मित्रमण्डल से त्यागण्य देन से इकार नर दिया। साम्यवादी मित्रया के दस नाय वे मित्रमण्डल से त्यागण्य देन से इकार नर दिया। साम्यवादी मित्रया के दस नाय वे मित्रमण्डलीय एकता एव उत्तरदायित्व ने मित्राल्य नो मम्प्रमान व द्याल नगा। यही नहीं साम्यवादी में भी अपन यदा पर रहत हुए सासनीय सम्मान व द्याल नगा। यही नहीं साम्यवादी में भी अपन यदा पर रहत हुए सासनीय सम्मान व द्याल नसन्तया में करते रहें। साथ ही साथ व सामकीय नीति के विकद्ध सावजनिक असत्तीय सं मी लाम उठात रहें। अत प्रधानमणी मोदिय रामाडीर (M Ramadict) न साम्यवादी में प्रया द्वारा पदस्थाग न करन पर उन्ह मित्रमण्डल से निटमासित करने का निणय किया था। इस पर राष्ट्रपति न साम्यवादी मित्रया को पदच्युत कर दिया और उनक स्थान पर नथीन मित्रया नी नियुक्तियों की थी।

मित्रमण्डलीय एनता का दूसरा प्रमाण एक अप्य पटना स भी प्राप्त होता है। फरवरी 1950 इ. म साम्यवादी मित्रया न निर्वाह-व्यय मत्ता (Cost of Living Bonus) की मांग वो अपने सहयायी मित्रया द्वारा अस्वीकृत क्य जाने पर त्यागपत्र दे दिव थ । प्रधानमात्री माशिय विदाल्त (M Bidault) न मोशिय रामाडीर (M Ramadier) का अनुगमन करते हुए स्यागपत्र नहीं दिया अपितु समाजवादी मित्रया कस्थान पर एम आर पी (M. R. P) एव अय सदस्यां की नियुक्तियां कर दी। कास म ग्रेट त्रिटेन की अपक्षा मन्त्रिमण्डलीय उत्तर दापित्व क सिद्धान्त के बारण अपशाकृत अधिक जटिल समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। फेंच मिनमण्डला म जिटेन की मौति एक ही दल क सदस्य नही होते और न बिटिय मि निमण्डलीय व्यवस्था के सफल सचालन जसा लम्बा इतिहास ही है। केंच मित्र मण्डल म प्राय विभिन्न एव परस्पर विरोधी विचारधाराओं के अनक दल होते हैं। उदाहरण के लिए, 1947 (नवस्वर) म राबट शमा द्वारा जिस मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया गया था उसम नियोजित अय व्यवस्था म विश्वास करने वाले समाजवादी एव मुक्त व्यापार और यदमान्यम नीति म विश्वास रखने वाले उग्र समाजवादी थे। ऐसे सयुक्त मित्रमण्डला मे प्रत्यक नीति विषयक प्रस्ताव पर गम्भीर विवाद होना स्वामाविक ही है।

फेंच प्रधानमन्त्री⁸

ततीय एव चतुष फेच गणराज्या के प्रधानमात्रा की स्थिति का अध्ययन अत्यात राचक है। ससदीय प्रणासी मं प्रधानमात्री की स्थिति केन्द्रीय होती है। वह

⁸ फेच प्रधानमात्री को प्रेसीडेण्ट ऑफ दी काउ सल आफ मिनिस्टस (President of the Council of Ministers) की सज्ञा दी जाती है। फेच शासन के

मिं नमण्डल का नेता एव यथाय कायपालिका होता है। लास्की के शब्दों में, प्रिटिश प्रधानमंत्री मिं नमण्डल के जान, जीवन एव मरण का कारण है। फेल प्रधान मिं नमी की शासन में एंसो के दीय स्थित नहीं थी। ततीय गणराज्य म प्रधानमंत्री समक्क्षी में प्रथम (primus inter pares) नहीं या और न व्यय मिं प्रया के समक्क्ष ही या। प्रश्नेक फेल में निमाण्डल म प्रधानमंत्री की समान स्थित एव व्यापक राज्य- नीतिक व्यक्तित्व वाले कई व्यक्ति हुना करते थे। उनमें से मुख तो अपने प्रपत्न देवों के प्रमुख एव भूतपूब प्रधानमंत्री भी होते थे। वे अपने व्यक्तित्व एव दलीय विचारों को सहुक ही प्रधानमंत्री के अधीन मानने को तैयार नहीं होते थे। अय दक्षा के नता ही नहीं, अपितु उसके अपने दल के महत्वाकाशी सदस्य भी प्रधानमंत्री वनने के सदैव इच्छेत हत्ते थे। काटर, रेने एव हेक के अनुसार, ''फेल दलीय नेता के प्रति जिटिश मिं नमक्ति का अभाव था और प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति एव विटिश प्रधानमंत्री की प्रतिका का भी उपभीग नहीं करता था।'"

चतुय गणराज्य के सविधान निर्माता फ्रेच प्रधानम ती को ब्रिटिश प्रधानमात्री की मौति शासन का यथाथ नेता बनाना चाहते थे । प्रधानमानी की मनीनीत होने के परचात नेशनल असेम्बली का विश्वास प्राप्त करना पडता था। 10 वह मित्रमण्डल के भवस्या की सुची पर राष्ट्रीय समा की स्वीकृति प्राप्त करता था । इस व्यवस्था स प्रधानमात्री के पद का महत्व बढ़ा था। मोशिये रामाडीर ने इस सम्बर्ध म कुछ स्वस्य परम्पराएँ डाली थी। उसने प्रधानमात्री चने जाने क बाद एक व्यक्तिगत वक्तव्य दिया था जो उसके सहयोगिया की सहयति मे निर्मित एक सामृहिक वक्तव्य नहीं था। इसके पश्चात उसने 'मिनमण्डलीय बेच पर अकेले ही स्थान ग्रहण किया था। रामाडीर ने प्रधानम तो की स्थिति को हढ करने की दिशा म एक जाय उल्लेख नीय काथ किया । उसने अपने मन्त्रिमण्डल के कुछ सदस्यों को निष्कासित करके मिनिमण्डल का पूर्निर्माण भी किया। इस प्रकार प्रधानमानी मित्रमण्डल के राज नीतिक आधारमूत स्वरूप मे परिवतन कर सकता था। तृतीय गणराज्य की तुलना म चतुथ गणराज्य के प्रधानमात्री को अपने सहयोगियों के साथ व्यवहार करने म विधिक स्वत तता एव शक्ति प्राप्त थी। पहले मित्रया द्वारा विभिन्त विधेयक सीघे असम्बली म प्रस्तावित किये जाते थे लेकिन चतुष गणराज्य के अ तगत सभी प्रस्ता-वित विधेयको पर प्रधानमात्री के हस्ताक्षरो का होना आवश्यक था । मन्त्रिया के द्वारा प्रस्तावित परस्पर विरोधी विधेयका पर विचार करने के लिए चत्य गणराज्य

अनेक पदाधिकारियो को प्रेसीडेंक्ट की सना प्राप्त है। यत यहाँ पिण्यमण्डलीय परिषद के अध्यक्ष क स्थान पर प्रधानम त्री शब्द का प्रयोग अनावश्यक अस्पटता से वचने के लिए किया गया है।

⁹ Carter Ranney and Hez, op at, p 149

में अंत विमागीय समितियों की व्यवस्था थी । स्पष्ट है कि प्रधानम थी मित्रमण्डल में एक समज्यात्मक कडी का काय करता था ।

लेकिन चतुय गणराज्य के अत्तगत भी अतिम सत्ता असम्बली के हाया म ही थी । मिनमण्डल को जिवदवास प्रस्ताव पारित होन पर पदस्याग करना पडता था। स्मरणीय है कि फास म बहुदलीय पद्धति के कारण प्रधानम त्री अत्यन्त साच समक्रकर काय करता है। चतुथ गणतात्र म प्रधानमात्री को मित्रयो की नियुक्ति करन एवं उह पदच्युत करने के अधिकार थे। लेकिन सयुक्त मित्रमण्डला का अध्यक्ष होत के नाते प्रधानमंत्री किसी मी दल को असतुष्ट करने की स्थिति म नहीं होता थी और इसी प्रकार न यह स्वविवेक संअपने मित्रयाकाचयन ही कर सक्ता था। कार्टर, रेने एव हेज¹¹ के अनुसार चतुष गणराज्य के जातगत केंच प्रधानमात्री की शक्ति म दुछ विद्व अवस्य हुई थी। प्रथम, प्रधानम त्री बहुमत का निर्माण करने वाले दला के नेताओं का समयन प्राप्त करने म सफल होन पर असम्बली का सरलतापूर्वक सामना कर सकता था। कठोर दलीय अनुशासन एव मित्रमण्डलीय उत्तरदायित का परस्पर महत्वपूरण सयोग हुआ था । ऐसी परिस्थितियो म मन्त्रिमण्डल ससदीय सहयोग की अपक्षा दलीय सहयोग पर अधिक निमर रहता है। इसी कारण यह मुकाव दिया गया था कि मिनिमण्डल में बामिल प्रत्येक दल का एक विमामहीन मानी होना चाहिए जो मिनमण्डल तथा दलीय मुख्य कार्यालय स सम्बाध रख सके। यह सुकाव अन्त तागत्वा ततीय न्यूइल (Queuille) मित्रमण्डल काल म क्रियाचित किया जा सका। प्रधानम ती की स्थिति को प्रमानशाली बनाने मे सहायक दूमरा कःरण यह या कि मिनमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्तान प्रस्तुत किय जाने के पूरे एक दिन पश्चात ही उस पर निचार किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त अनिश्नास प्रस्तान के मत नाम लेकर पुकार जाने की रीति (roll call role) से लिये जाते थे। निम्न सदन-चेम्बर ऑफ डिप्टीज के द्वारा स्पष्ट बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत होने पर ही मिनमण्डल का पतन होता था। 1954 ई म स्पष्ट बहुमत के स्थान पर सामाय बहुमत की व्यवस्था कर दी गयी थी। प्रधानमात्री इन व्यवस्थाओं का लाम उठा कर प्राम विधिक प्रस्ताव को विश्वास सम्ब धी घीषित करके उन्ह पारित करन म सफल हो जाता था। इसके अतिरिक्त मिनमण्डल उच्च सदन-काउ सल-के प्रति चतुम गणतात्र मे उत्तरदायी नही था। अत मं प्रधानमात्री को राष्ट्रीय समा को मग करने नी शक्ति प्राप्त होने के कारण उसकी शक्ति म वृद्धि हुई थी।

फेंच प्रधानमंत्रियों के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में कोई सामाय विचार प्रस्तुत करना सम्मव नहीं है। एक बात स्पष्ट है—क्तीयेखी (Clemenceau), पांकारे (Pomcare) एवं वियानो (Briano) जसे महान प्रधानमंत्रियां के कायकाल वर्षसाङ्कत

¹¹ Carter, Ranney and Hez op cst, p 150

लम्बे थे । वे दलीय नता होने के कारण नही जपितु जपने व्यक्तित्व क कारण दीघकाल तक अपने पद पर बने रहे। फेच प्रधानमात्री के लिए हढ निश्चयी एव सुनिश्चित कायक्रम वाला होने की अपेक्षा समकौत की कला में दक्ष होना अधिक आवश्यक है। काटर, रेने एव हेज के अनुसार ' उसे समभौत की कला म दक्ष एव सम विधारमक प्रवित्त का होना चाहिए तथा उसे अपने कायम्म को इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए कि उसस असहमति रखने वाले भी अस तुष्ट न हो। उसको विभिन्न एव अधिकाधिक समूहो का विश्वास और यदि सम्मव हो तो मित्रता अजित करनी चाहिए। उसे निश्चित रूप स गणत त्रीय विचारधारा का होना चाहिए ताकि वह परस्पर सदस्यों मे और मित-मण्डल एव राष्ट्रीय सभा ये मतक्य स्थापित करने में सफल हो सके।" 1946 ई म हैनरी क्यूइल (Henry Queuille) एक वय से अधिक समय तक प्रधानम त्री रहे थे। देमेल यासमभौत की कलाम दक्ष थे। उनके मित्रव काल मे युद्ध जजरित फास ने पयाप्त उत्तति की थी।

1870 से 1958 ई तक के काल की फोच साविधानिक व्यवस्था सासद प्रमुख थी। लेकिन पाचवे गणराज्य म स्थिति मिन है। अद कायपालिका पहले की अपेक्षा शक्तिशाली एव इट है। पाचने गणराज्य (1958 ई) के अत्तगत प्रधानमात्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन वह सामा यत ससद के प्रति उत्तर-दायी होता है। प्रधानम ती ही राष्ट्रपति के समक्ष मेत्रियों के नामा को उपस्थित करता है और राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है। मिनमण्डल की बैठको की अध्य-क्षता राष्ट्रपति करता है न कि प्रधानम ती । तृतीय गणराज्य मे भी मी निमण्डल की वठका की अध्यक्षता राष्ट्रपति ही करता था और उसका अपना मत मी होता था। चतुष गणराज्य के अत्तगत राष्ट्रपति मित्रमण्डलो की बैठको की कैवल अध्यक्षता करताया। पाचवें गणराज्य मे प्रधानमात्री की स्थिति राष्ट्रपति की तुलना में हुय है। प्रधानम नी देश की सुरक्षा एव विधियों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है। वह ससद मे शासन का प्रमुख वक्ता है लेकिन उसे सदन का नेता नहीं कहा जा सकता ।

फास म बहुदलीय पद्धति के विकास के कारण फेंच प्रधानमात्री का कायकाल अधिक लम्बानहीं होता। 1873 ई से 1928 ई तक फ्रेच प्रधानमात्री का औसत नायकाल 18 माह से अधिक नही रहा है।

फ्रेंच गणराज्य का राष्ट्रपति

ततीय गणराज्य के अन्तगत फ्रेंच राष्ट्रपति की स्थित अत्यात नमजार घी। राष्ट्रपति को भेंच व्यवस्थापिका के दोनो सदना की संयुक्त बठक—राष्ट्रीय समा—के यहुमत म 7 वय के लिए चुना जाता था। प्रत्येक फेंच नागरिक राष्ट्रपति चुने जाने ^का अधिकारी होता था । राजवद्म के सदस्य इसका अपवाद था । राष्ट्रपति की शक्तिया ना प्रयोग मित्रमा द्वारा निया जाता था। उसने नाम पर दिय जान वाले आदणा पर किसी न किसी मात्री के हस्ताक्षर अनिवायत होते थे। मात्रीगण राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी न होकर निम्न सदन—चेम्बर ऑफ डिप्टीज—क प्रति उत्तरदायी होते थे। राष्ट्रपति पर चेम्बर आफ डिप्टीज को महानियोग लगान का अधिकार प्राप्त था। सीनेट इसकी जाज करती थी।

फेच राष्ट्रपति की स्थिति अवद्यानुगत सर्वैधानिक राजा (Non hereditary Constitutional Monarch) जैसी थी। वह राज्य का सम्मानास्पद अध्यक्ष था। वह समारोहो की अध्यक्षता करता था, दलीय ट्टिंट से निष्पक्ष तथा पक्षणतपूर्ण दलीय राजनीति से दूर रहता था। राष्ट्रपति द्वारा इन विशेषतामा का अतिक्रमण कियं जाने पर उसे उसका प्रतिफल भी भोगना पडता था। उदाहरणाथ, 1877 ई म राष्ट्रपति मकमोहन क अधिनायकतः त्रीय शक्तियो को अजित करने के प्रयत्न की निवा की गयी थी एव 1924 ई म दलीय पक्षपात के लिए राष्ट्रपति मिलेरा ड (Millerand) को पदत्याग करना पडा था। फासीसी लोग शक्तिशाली कार्यपालिका के प्रति अधिक स देहसील रहे है। लुई नेपोलियन ने गणतात्र का समाप्त कर साम्राज्य की स्थापनी की थी। अत कासीसियाको शक्तिशाली राष्ट्रपतिका विचार स्वीकाय नही था। इसी प्रकार राष्ट्रपति को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित करने का विचार भी उन्ह स्वीकाय नहीं था । सकट के पश्चात यह विचार जनता मे अधिकाधिक वल पकडता गया कि राष्ट्रपति को शानशीकत विहीन, पूणत गणत शीय एव कम लोकप्रिय होना चाहिए । तृतीय गणराज्य के अत्तगत केवल एक राष्ट्रपति—पाकारे—प्रथम श्रेणी का राजनीतिन था। योग्य तथा प्रमुख राजनीतिनो—क्लीमें सो एव व्रियानो—को राष्ट पति यद के लिए निरतर अस्वीकार किया जाता रहा। ततीय गणराज्य के फ्रेंच राष्ट्रपति के सम्बाध में सर हेनरीमेन का यह मत था कि 'फ्रेच राष्ट्रपति के अतिरिक्त किसी मी जीवित पदाधिकारी की स्थिति अधिक दयनीय नहीं है। फास के प्राचीन नरेश ही राज्य एव शासन करते थे। "सवैधानिक राजा", मोशिय दीयरस के अनुसार, "राज्य करता है शासन नहीं । सयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति शासन करता है पर उ राज्य नहीं। यह केवल फच राष्ट्रपति के ही माम्य म है कि वह न राज्य करे और न शासन ।' अत राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश सम्राट की तुलना मे हेय है। काटर, रेने एव हेज के अनुसार राजाओं के प्रति अनेक पीढिया से जो श्रद्धा का मान पापा जाता है उसका सामान्यत फेच राष्ट्रपति के लिए अभाव है। उसके अधिकाश काय समारोहा रमक होते थे । लेकिन ततीय गणराज्य के राष्ट्रपति की स्थिति सामा यत ठीक नहीं थी वार्थीन (Barthon) का यह स्पष्ट मत है कि राष्ट्रपति निर्जीव शासक नहीं है । वह सिक्रिय परामश देकर पर्याप्त प्रभावशाली हो सकता है क्योंकि मात्रीगण उसके परामश नी पद एवं अनुभव के कारण आदर से ग्रहण करते हैं।

दितीय विश्व युद्ध के पश्चात फास के नाजी निय त्रण से मुक्त होने पर श्रिगास ने सक्तिसाली कायपालिका की स्थापना का समयन किया था । वे राष्ट्रपति को वास्त विक अध्यक्ष वनाने क पक्ष म थे। प्रथम, डिगाल राष्ट्रपति को ससद से स्वतः न रखना पाहते थे अर्थात् उनका मत था कि राष्ट्रपति को ससद की अपेक्षा एक अय वहद निकाय द्वारा चुना जाना चाहिए। दितीय मिन्या को राष्ट्रपति द्वारा चुना जाना चाहिए। दितीय मिन्या को राष्ट्रपति द्वारा चुना जाना चाहिए एव उसके प्रति ही वे उत्तरदायी होने चाहिए। तिथि, राष्ट्रपति को ससद को मग मर्क जनता से अपील करने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन डिगाल के मत को स्वीकार नहीं किया गया। 1946 ई के सविधान के प्राष्ट्रप (Draft) के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन गया। 1946 ई के सविधान के प्राष्ट्रपति का कृतान की नाम को अध्यक्ष के साम को गयी थी। फलस्वरूप दक्षीय राजनीति के दबत्वल में राष्ट्रपति का दूवना अनिवाय था। राष्ट्रपति को सुनीय गणराज्य के अत्यत्व प्राप्ट सभी विशेषाधिकारों से विवत्त कर दिया गया था एव क्षमादान का अधिकार उससे लेकर एक यायिक समिति को देने का प्रस्ताव किया गया था। प्रधानम नी की नियुक्त करने की शक्ति मी उससे ले तेन का प्रस्ताव किया गया था। उसे प्रधानम त्री के लिए विभिन्न नामों को अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तावित करने का अधिकार यान दिया गया था। जनता ने इन प्रसावों के समक्ष प्रस्तावित करने का अधिकार यान दिया गया था। जनता ने इन प्रसावों के अध्यक्ष कर दिया।

चतुथ गणराज्य के अन्तर्गत राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रीय समा (National Assembly) एव गणराज्य परिषद (Council of the Republic) के समुक्त अधि-वेदान म, जिसे काग्नेस की सज्ञा दी गयी थी, सामाय बहुमत से किये जाने की व्यवस्था की गयी थी। उसका कायकाल 7 वय था एव राष्ट्रपति पद पर कोई व्यक्ति एक बार ही निर्वाचित हो सकता था। दसद्रोह के लिए उस पर राष्ट्रीय समा द्वारा दोपारोरण होंने पर सर्वाच्य त्यायालय (High Court of Justice) म मुकदमा चलाया जा सकता था। राष्ट्रपति पद के लिए कोई बहुताएँ एव आयु निर्धारित नहीं की गयी थी। प्रारंक 21 वर्षीय फ्रेच नागरिक जिसे नायिक तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे एव जो राजनद का सदस्य नहीं था, राष्ट्रपति पद पर चुने जाने की योग्यता रखता था।

सविधान के अनुसार राष्ट्रपति की समस्त शिक्तवा का प्रयोग उसके नाम पर मिनमण्डल ने अध्यक्ष (प्रधानमानी) एव अय सनियो द्वारा किया जाता था। राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए राजनीतिक रूप से उत्तरदायी नहीं था, देशद्रोह इसका एकमान अपनाद था। मिनमण्डल, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, सवधानिक समिति एव दण्डाधिमारिया की सर्जोच्च समिति को अध्यक्षता राष्ट्रपति करता था। अध्यक्ष के रूप म उसका काय केवल समिति को अध्यक्षता राष्ट्रपति करता था। अध्यक्ष के रूप म उसका काय केवल समितियों के निषया को घोषित करना एव कायवाहिया को सुरक्षित रखना मान था। देकिन जब मन्याय को बैठक राजनीतिक उद्देश्य हेतु विग्रेपकर मिनमण्डल (Cabmet) के रूप मे होती थी, तो राष्ट्रपति अनुरक्षित उत्तर था। तृतीय मणराज्य के राष्ट्रपति को सद्धारति विषयी प्रस्तातिक करने का अधिकार प्राप्त पान सो लिकन चतुष स्थाराज्य के राष्ट्रपति को सद्धार्थन के स्थार स्थ

या। वह राष्ट्रीय समा से सन्दर्श के माध्यम से अप्तयक्ष रीति से वाहित विधिया क निर्माण का प्रस्ताव कर सकता था और ऐसे स देशा का प्रधानमंत्री या किसी मंत्रा द्वारा अनुमीदित होना आवश्यक था। तृतीय गणराज्य के अतगत राष्ट्रपति को सिद्धातत निर्पेषाधिकार प्राप्त था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विषयक विधि नहीं यन सकता था। चतुष गणराज्य म राष्ट्रपति को निर्पेषाधिकार की धर्मि प्राप्त नहीं थी। यदि पारित विधयकों को प्रस्तुत किये जाने के दस दिन और आवश्यक विधेयक का पाच दिन के अदर राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता था, तो राष्ट्रीय समा के अध्यक्ष को ऐसे विधेयकों की स्वीकृत करने का अधिकार प्रदान किया

राष्ट्रपति को नियुक्ति सम्ब पी अधिकार प्राप्त थे। वह मिन्रया, काउन्सल आफ स्टंट के सदस्यो, ग्राण्ड चान्सलर (Grand Chancellor of the Legion of Honour), त्वर्शच्च परिपद (Supreme Council) एव राल्ट्रीय सुरक्षा समिति कं सदस्यो, रेक्टरो, प्रोफेक्टो, राजदूतो, विशेष दूता एव उच्च के दीय प्रशासकीय अधिकारियों को नियुक्त करता था। वह सभी स्त्रियों पर हस्ताक्षर करता एव जन्हें अनुमोदित करता था। वह सेना का सर्वोच्च केतापति भी था एव यापपानिका करता था।

क्रेंच राष्ट्रपति को सिद्धात म ततीय एव चतुथ गणराउय मे ध्यापक धांतियी प्रवान की गयी थी। पर तु व्यवहार में वह शक्तिहीन या। उसका पद शक्ति का नहीं अपितु प्रसाव का था। इसका प्रमुख कारण यह था कि राष्ट्रपति के प्रत्येक आदेश पर किसी न किसी मानी के हस्ताक्षर होने आवश्यक थे। लेकिन ब्रिटिश सम्राट की तुलना मे उसका प्रमाव अधिक था। ब्रिटिश सम्राट न दो शताब्दिया से मित्रमण्डस की अध्यक्षता नहीं की है। एव राष्ट्रपति की मित्रमण्डल की अध्यक्षता करने एवं वाद विवाद में भाग तेने का अधिकार प्राप्त था। ब्रिटिश सम्राट के निपरीत देश की राजनीति म सिक्य रहने के कारण उसके (फ़ैच राष्ट्रपति के) परामश अनुमव पर आधारित हात थे। राष्ट्रपति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति राष्ट्रीय समा की सहमति से प्रधानम नी को मनोनीत करना था। ब्रिटेन में काम स समा के बहुमत दल का नेता ही प्रधानमात्री पद के लिए राजा द्वारा आर्था बत किया जाता है तेकिन फास में बहुदलीय पद्धति होने के कारण राष्ट्रीय समा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, श्रत राष्ट्रपति को प्रधानमात्री के चयन मं पर्याप्त स्विविवेकीय अवसर प्राप्त हो जात हैं। लेकिन प्रधानमात्री का चयन करना एक अत्यात नाजुक काय है। इस हेतु कुछल एव धैयवान वार्ताकार के गुणो का राष्ट्रपति म होना आवश्यक होता है। चतुव गणराज्य के सविधान के निर्माण के समय राष्ट्रपति को सविधान के सरक्षक की सना दी गयी भी । 1947-48 ई के सकटवालीन शरद ऋतु म विभिन्न राजनीतिक समूहा ने राजनीतिक एव आर्थिक विवादों के सादम मा राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की अपील की भी । बदर्पि चत्य गुणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति ओरियल (Aurial) ने ऐसे विवादों ने ह्न्डडेर नहीं किया या परन्तु विसंकुल मित्र परिस्थितियों में नवम्बर 1950 ई एवं करेन 1951 ई म राष्ट्रपति ओरियल ने शासन के स्थापित के लिए एक क्षाप्रकार की पदारुढ रखने हेत् दो बार हस्तक्षेप किया था। ततीय एव बहुई रसटार के उन्नेजेड सामा य योग्यता क व्यक्तियों को ही राष्ट्रपति चुना जाता रहा कर

फ्रांस के पांचवें गणराज्य (1958 ई) का राष्ट्रराहे

कास के पाचने गणराज्य के सनिधान म राष्ट्रपति हैं इ राजनाज्य की पूर्व है। सद्यति को 7 वय के तिए एक निर्वाचक-मन्द्र हुए निर्वेचन का बन्द है (अनुचंदेद 6 एव 7) । ससदीय सदस्य, समुद्र गर के बीए की नामान्य मुक्तिरी एवं असम्बेलियों के सदस्य और नगरपालिहाओं के लेन्द्रिक प्रतिकेटिक राज्यीत के निर्वाचक मण्डल के सदस्य होते हैं । निर्वाचक-मार्च वें न्या केंस के के करियों दियों की सख्या सबसे अधिक होती है। प्रयम नतान में न्यूट बाह्य प्राप्त कार्य दान व्यक्ति को राष्ट्रपति निर्वाचित घाषित दिस जान है। वॉर जेवन करान = जिले प्रत्याक्षों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हाटा ना दिया नहरून हुन्य है और द प्रत्याशी अपने निकटतम उम्मीदवार की नुकान में आँचद मार प्राप्त कारण है उसी का निर्वाचित घोषित कर दिया जाना है। ⁻⁻⁻ न्यूयर्ट नड के निस्त हान की निस्तृति है उनके कतच्या को अस्थायी रूप म सीनट है उच्छ द्वार कर्नाट्ट कि क्राया है। 🗝 पति नी मिर्वाचम पद्धति को नाद्र साराज्य है की है कर करा करा है कि का पति पव के लिए यदि देवड दो या ईंग में स्टब्स्टिंग्ड में हैं में स्टब्स्ट में ही राष्ट्रपति के चुन बान की अन्यान्त हुन्हें र अन्ते वृहें गुण्येत ज्वान्य के व्ह उद्देश ही समाप्त हा बाटा ह कि प्रकृति - स्तूष्टें कप्तू हा प्रवित्ति हूँ त चाहिए । द्वितीय मतदान की की ब्यान्त र प्रस्ते इस क्षेत्र हैं कर का समार्थ है कि मतवातामा न कई महिल साम है के किए सम्बद्ध करना है की प्रत्याशी का निदायन व हैं औ काय एव शक्तिया

और सावजनिक शक्ति का उचित उपयोग किया जाता है तथा राज्य कायम रहता है। राष्ट्रीय स्वत त्रता क्षेत्रीय वक्षुण्णता एव समझौत और सि धया का वह सरक्षक है। 13

वह प्रधानमात्री को नियुक्त करता है। 14 प्रधानमात्री द्वारा त्यागपत्र प्रस्तुत करने पर वह उसे स्वीकार करता है। प्रधानम त्री के परामश पर वह अप मित्रयो को नियुक्त एव पदच्युत करता है। वह मिनमण्डल की अध्यक्षता करता है। 18 अनुक्छेद 8, 11, 12 16 एव 54 56, 61 सम्बाधी कार्यों को छोडकर राष्ट्रपति के शप सभी कार्यों पर प्रधानम नी या अप सम्बन्धित मात्री के हस्ताक्षर होन चाहिए।16 वह विधियो की घोषणा करता है तथा ससद की विधिया पर पुनर्विचार का आदेश दे सकता है। 17 ससद के सत्रकाल में शासन या दौना समाआ के संयुक्त प्रस्ताव पर वह सावजनिक शान्ति अथवा सिंध सम्बाधी किसी विधेयक पर जनमत सप्रह का आदेश दे सकता है। यदि विधेयक के पक्ष मे जनता मत देती है तो राष्ट्रपति को 15 दिन के मीतर उस स्वीकृति प्रदान कर देनी चाहिए। 18 प्रधानमात्री तथा दोनो सदनो क थध्यक्षा वे परामक्ष से वह राज्दीय समा को विघटित कर सकता है लेकिन विघटन के कम स कम 20 दिन और अधिक से अधिक 40 दिन के सीतर सामा य तिर्वाचन ही जाने चाहिए । इसके परचात पुन विघटन सम्मव नहीं है । राष्ट्रपति मनि-मस्पिद के अध्यादेशा एव आज्ञाओं पर हस्ताक्षर करता है। उह वह दोनों सदना को भेज सकता है जहाँ वे पढ़े तो जाते है पर तु उन पर विवाद नहीं हो सकता।³⁵

राष्ट्रपति को नियुक्ति सम्ब घी व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। सनिक एव असनिक पदा जैसे म ती, राजदूती विशेष राजदूती, मुख्य चा सत्तर, तेखाकत कार्यातय का प्रमुख, समुद्रपार राज्य के प्रतिनिधि एव पदाधिकारी प्रमुख अधिकारियों, शिक्षा अधिकारियो (रेक्टरो) एव के द्वीय प्रशासन के निर्देशको की नियुक्ति वह मिन-परिपद के निश्चय के अनुसार करता है। 20 विदेशा म वह राजदूता की नियुक्ति करता है एव विदेशी राजदूती का स्वागत करता है। वह सशस्त्र सेनाओं का अध्यक्ष है और राष्ट्रीय सरका की उच्च परिपदो एवं समितिया की अध्यक्षता करता है। al

¹³ अनुष्केंद 5

¹⁴ अनुच्छेद 8

¹⁵ अनुच्छेद 9

¹⁶ अनुच्छेद 19

¹⁷ अनुच्छेद 10

¹⁸ अनुच्छेद 11

¹⁹ जनुच्छेद 18

²⁰ अनुच्छेद 13

²¹ अनुब्छेन 15

राष्ट्रपति को सकटकालीन दक्तियाँ प्राप्त हैं। व गणतात्र की सस्याओ, राष्ट्रीय स्वत त्रता एव असण्डता तथा अ तर्राष्ट्रीय बचना व पालन को सतरा उत्पन्न हान के कारण सबधानिक शासन का चलना कठिन होने पर राष्ट्रपति प्रधानमात्री एवं समाक्षा ने अध्यक्षा तथा सबैधानिक परिषद स परामद्य करके परिस्थित का सामना करने के लिए आवश्यन भदम उठा सनता है । अपन निणय नी मुचना वह स देश के द्वारा देता है। इर विश्रप शक्तिया के प्रयाग काल म राष्ट्रीय समा मग नहीं की जाती है।

राप्ट्रपति को क्षमादान की दालियाँ प्राप्त हैं। वे उस दण्ड वम करने का अधि-नार है। राष्ट्रपति यायपालिका नी स्वतात्रता ना सरक्षक होता है तथा याय-पालिया भी उच्च परिषद * की अध्यक्षता करता है।

स्यिति

पौचर्षे फेच गणराज्य वा राष्ट्रपति सविधान की धुरी है । दश के राज-नीतिता म सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति डिगाल को प्रथम राष्ट्रपति चुनागया था । राष्ट्र पति को सविधान द्वारा व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। फ्रांस में शक्तिशाली राष्ट्र-पति को प्राय सन्देह की हृष्टि स दखा जाता था। लई नवीलियन न दितीय गणराज्य का राष्ट्रपति होन पर अपन को सम्राट घोषित निया था, फलत तीसरे गणराज्य म राष्ट्र-पति का नाममात्र की शक्तियाँ प्रदान की गयी थी। वह सबस कमजोर राज्याध्यक्षी म स या तथा अप्रत्यक्ष रीति स चुना जाता या । विधानमण्डल के दोना सदनो को विघटित करन की अपनी विधिक शक्ति का 1877 ई के पश्चात उसन कमी प्रयोग नहीं निया। चतुष गणराज्य के राष्ट्रपति की स्थिति म भी कोई विशेप आतर नहीं या । इस ऐतिहासिक परिपक्ष्य म पांचवें गणराज्य के राष्ट्रपति की स्थिति का मूल्या-क्न महत्वपूण है।

राष्ट्रपति कायपालिका का यथाय अध्यक्ष है और आतरिक एक वैदेशिक नीति का निर्माता है। वह राज्य व शासन का वास्तविक अध्यक्ष है। उसे विधानमण्डल को निया त्रित करने सम्बाधी व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह विधानमण्डल को विघटित कर सकता है। विधानमण्डल द्वारा द्यासन के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने पर राष्ट्रपति की असम्बली को विघटित करके नवीन निर्वाचन का आदेश देने का अधिकार है। उसे व्यापक संकटनालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं। डोरणी पिकिस्स (Dorthy Pickles) ने अनुसारजनरल डिगाल इन अनुच्छेदो को सीमित एव निश्चित अवस्था म ही प्रयोग करना चाहते थे तथा राष्ट्रीय सकट के समय रक्षित शक्ति के रूप म ही इस व्यवस्था का प्रयोग करन

²² अनुच्छेद 16 23 जनुच्छेद 17

²⁴ यायपातिका की उच्च परिषद (High Council of the Judiciary) की याया धीरा पर अनुशासन सम्बन्धी निय तथ प्राप्त है। इसम 9 सदस्य होत हैं जिह राष्ट्रपति एवं विधि मात्री मनोनीत करता है।

के पक्ष में थे। सकटकालीन शक्ति के प्रयोग के बारणा के सम्ब ध म आलोचको को आपित नहीं है। भुरव आपित सकटकालीन शक्ति या सम्ब धी पद्धति पर है। " राष्ट्र पित स्वय को शक्तिशाली बनाने के लिए इन खित्मा का दुरुपयोग कर सकता है। राष्ट्र पित को सम्ब ध म निषम लेने का एकाधिकार प्रास्त है। विधानमण्डल के दोना सदनो एव सर्वधानिक परिपद से उसे केवल परामदा लेना पडता है। परन्तु क्या यह परामदा लेना पडता है। परन्तु क्या यह परामदा लेना पडता है। परन्तु क्या यह परामदा लेका पडता है। परन्तु क्या यह परामदा व घनकारी है ? यह स्पष्ट नहीं है। आलोचको का यह मी मत है कि यदि विधानमण्डल के दोना सदना एव सर्वधानिक परिपद के अधिवेशन ही न हो तो सकटकालीन खित्मों को प्रियानित करना असम्मव है। दूसरा प्रस्त यह उठता है कि क्या राष्ट्रपति की सकटकालीन खित्मों पर कोई प्रतिव ध है ? क्या राष्ट्रपति सिव धान के किसी माग को अस्पकाल के लिए निरस्त कर सकता है ? इसी स सम्बधित एक अस्य प्रस्त यह भी है कि क्या सकट काल म राष्ट्रपति को अपने कार्यों को सुवना ससद को देनी चाहिए?

पायचे फ्रेंच गणराज्य के राष्ट्रपति को मारतीय राष्ट्रपति एव अमेरिकी राष्ट्रपति से तुलना नहीं की जा सकती है। ब्रिटिच राजा एव भारतीय राष्ट्रपति द्वारा मिन मण्डल की अध्यक्षता नहीं की जाती है। इसके विपरीत, फ्रेंच राष्ट्रपति अपन मिन मण्डल की अध्यक्षता करता है। ततीय गणराज्य का राष्ट्रपति मिन मण्डल की अध्यक्षता करता है। ततीय गणराज्य का राष्ट्रपति मिन मण्डल की अध्यक्षता करता था पर तु उस मतदान का विधिकार प्राप्त नहीं था। मारतीय राष्ट्र पति को सामा यत प्रधानम मी की नियुक्ति में निर्णायक चिक्त प्राप्त नहीं है। फेंच राष्ट्रपति को फांच में बहुदलीय पढ़ित के कारण प्रधानम मी के चयन म यवाष चिक्त प्राप्त है। प्रथम राष्ट्रपति दिवाल के प्रभाववाली व्यक्तित्व ने इसमें और अधिक योग दिया था तथा राष्ट्रपति की सकट-काल की खिनत्यों ने उसे और अधिक विकर्ताली बाा दिया था। सकटकालीन चिक्तिया का उपभोग राष्ट्रपति द्वारा विना में प्रमण्डल की सलाह से किया था सकता है। त्रिक्त अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में उन्नकी स्थित है है। अमेरिकी राष्ट्रपति को खकता है। की कमेरिकी मान मण्डल उनके प्रति ही उत्तरदायी होता है। के पण्डाज्य के आताचा होता है। को सित्त से निर्वाल से सिक्त स्थापक चिषक चिक्तवाली होता है। अमेरिकी मिनमण्डल उनके प्रति ही उत्तरदायी होता है। के पण्डाज्य के आताच सित उत्तरदायी है।

फेच राष्ट्रपति राष्ट्र का चालक चक्र है। सिंचमण्डल को स्थित उसके सामने गोग है। वह उसे आच्छादित कर सकता है। उस पर वेचल महानियोग का एकमान प्रतिव य है। परन्तु महागियोग की रीति वडी जटिल है। देखड़ोह जैसे गम्प्रीर अराध के लिए ही उस दोपी ठहराया जा सकता है। दोना सदता द्वारा महानियोग प्रस्ताव जुले मतदान म कुल सदस्य-सस्या के स्पष्ट- बहुमत से पारित होने पर ही राष्ट्रपति पर महानियाग लगाया जा सकता है। सत्यस्यात उच्च गायालय (High Court of

²⁵ Dorothy Pickles The Fifth French Republic, p 143

सदस्या का एक निकाय होता है।-स्ट्राग²⁷ के अनुसार पाँचवे मणराज्य के अत्तवत फास मे अर्द्ध-गणत त्रीय पद्धति की स्थापना की गयो हैं जो जादिक शक्ति-पृथक्करण पर आघारित है। सविधान के किया वयन के प्रथम चार वर्षों म डिमाल द्वारा की गयी उसकी व्याख्या एवं मूल मतब्यो म बडा अतर था। बृद्धावस्था तथा अपने ऊपर होने वाले आक्षमणा एव आलोचनाओं के फलस्वरूप डिगाल ने अपने हटने के बाद को अवस्था पर विचार गरना प्रारम्म कर दिया था। अक्टूबर 1962 ई म राष्ट्रीय समा के शीतकालीन अधि-वेषान के अतिम दिना म राष्ट्रपति डिगाल ने राष्ट्रपति को सावभीमिक मताधियार फ आधार पर चुनने एव सविधान म तत्सम्ब घी सधोधन करने का प्रस्ताव किया। 28 अनट्वर, 1962 ई को इस प्रस्ताव पर जनता की सहमति प्राप्त करन व लिए राष्ट्रपति ने जनमत सग्रह की घोषणा की। जनमत सग्रह के इस प्रस्ताय की अपुच्छेद 89 र अनुगार ससद की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत नही विया गया, फलत दश म ग्रथमनिर गरिराय उत्पन्न हो गया । राष्ट्रीय समा ने मित्रमण्डल के विच्छ वविध्याम का प्रम्नाव गाणि किया, ससद को विषटित कर दिया गया और नवीन नि शाउन ह बादन द दिव गत । प्रस्ताबित जनमत-सग्रह मे जनता द्वारा राष्ट्रपति वा प्रम्नात त्रहमन म स्वाहत हो गया और संविधान में आवश्यक संशोधन कर दिया गया। इम प्रकार, द्रांग व अगा-नसार, ससदीय प्रजात न की डिगाल Plebischary Pre.Leacs म गरियाना मान में सफल हुए।⁸⁸

प्रित्रमण्डल पाचने फच गणराज्य वे सनिधान म महिन्नस्टर की ध्यवस्था की गया है। राष्ट्रपति प्रधानमानी की निमृत्ति गरता है जार बहुन्दर्श 🔻 परामधी पर अध मित्रयों की नियुक्ति करता है। ¹⁸ उमझ (राष्ट्रति) छा पदच्यून नंभा ना औरझा है। मित्रमण्डल (शासन) ससद र प्रति उन्टन्टर्स है। होगान ,यसभा ना ना प्रतीत होता है कि फास म मस्रीय प्रमान का क्यान की गर्रा रे। बर्गा ह कर् स्वीकृत विटिश संसदीय राजगण्डिर च र् पंत रुपा, ल की पाल्यमण्ड राज स्वर् में अनेक अतर है। राष्ट्रपति निक्निक-एक द्वारा पूरा नाता है या विन्य संदर्भ अल्पमत म होत का 1952 हैं, के बाराज अमर्थित गुण्डा के के

²⁶ अनुच्छेद 68

^{27 &}quot;It is a reconfessional spites " based or section powers"—Sizing . Modern Political Cambridges.
28 Ibid, p. 251 28 Ibid , p 251

²⁹ बनुन्छद 8

³⁰ अनुन्द्रेद 10

राष्ट्रपति का भी प्रत्यक्ष रीति से चुना जाने लगा है। मिनिमण्डल के सदस्य ससर के प्रति उत्तरदायी होते हैं पर तु वे ससद के सदस्य नहीं होते हैं। स्पष्ट है कि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को प्रभावकाली ढम से क्रियाचित नहीं किया गया है जयाँव मिनिमण्डल पर दलीय अनुवासन तथा मतदाताओं का प्रभाव नहीं है। राष्ट्रपति को व्यापक शक्तिया प्रदान की गयी हैं। वह वास्तव म प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित राष्ट्र का प्रतिनिधि है। उसे ससद को विषयित करने की शक्ति प्राप्त है। ससद का अधि वेशन मो केवन 5 में सह होता है। हमस द्वारा पाष्ट्रपति का विरोध करने पर राष्ट्र पति उसे अभ करके नवीन निर्वाचन का आदेश हे सकता है। राष्ट्रपति को व्यापक सकदनालीन शक्तियाँ भी प्राप्त हैं।

फेच प्रधानमात्री विटिश प्रधानमात्री की साति मित्रमण्डल का नेता नहीं है यद्यपि सिवधान के अनुसार वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्तरवायों होता है। विधिया को निया वित करने का वायित्व उद्यक्ता है। वह शासनत त्र को संपालित करता है, सैनिक एव असैनिक अधिकारिया की नियुक्ति करता है तथा मित्रयों को अपनी जुछ शक्तिमाँ हरता तरित कर सकता है। वह आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति की अनुपत्थिति या उपने ह्यारा अधिकृत किय जाने पर उद्यक्ते स्थान पर मित्रमण्डल तथा उच्च परिपदा और राष्ट्रपति की अधीन राष्ट्रपति को समान स्थान स्थान स्थान वर सहित्र है। विविध्य चतुष्य गणराज्य के सविधानों के अधीन राष्ट्रपति उत्तर प्रधानम त्री नियुक्त कर सकता या। इन व्यवस्था आ को पाँचने गणराज्य ने सविधान म कोई स्थान नहीं है। फन प्रधान मंत्री मित्रफल को अध्यक्षता नहीं करता। उसकी स्थान नहीं है। फन प्रधान मंत्री मित्रफल की अध्यक्षता नहीं करता। उसकी स्थित राष्ट्रपति के समस गोण है। वह सब्द में सामक का अपने करता। वसकी स्थित राष्ट्रपति के समस गोण है। वह सब्द में सामक का अपने करता। वसकी स्थान प्रधानम में की मौति ससद का नता नहीं होता।

जमेंन कार्यपालिका [GERMAN EXECUTIVE]

प्रसा (Prussia) के नेतृत्व म 1871 ई म जमन राष्ट्र ना जम हुना था। प्रसा के प्रधानमंत्री (चा सलर) जिन्स विस्माक ने रक्त एवं लोह भी नीति स जमनी के एकीपरण एवं निर्माण म सर्वाधिक महत्रपूण भूमिका ना निवाह किया और प्रसा में होहुनजातन राजवसा के ज्योग जमन साम्राज्य ना जम्म हुना। जमन साम्राज्य गाजारी पर प्रसा नी क्रकुल एवं विक्तिसाली सामत-व्यवस्था ना प्रमाव पत्रा है। प्रसा नी जनता प्राचीन रोमना की नीति सम्राट हारा गामित होना पनना सोमाव समाक स्थान ने पत्रा हो सम्राठी । प्रसा नी जनता प्राचीन रोमना की नीति सम्राट हारा गामित होना पनना सोमाव सममती थी। प्रसा भी सासन प्रचाली क तीन मुख्य आधार थ—(1) जमादरार (Jun Lets) हारा समयन, (2) समतावान नीकरसाही एवं (3) गतिनाती सना।

³¹ अनुष्ठ 21

हंगेलवाद का प्रशा के जन जीवन पर स्पष्ट प्रभाव था। राज्य का जन जीवन पर पूण नियन्त्रण था।

जमन साम्राज्य (1871 ई) 25 राज्यों का सघ था। फाइनर के अनुसार 1918 ई तक जमनी में कोई उत्तरदायी सरकार नहीं थी। 12 समस्त सिक्त जमन सम्राट मं अधिष्ठत थी। प्रधानम नी को वह नियुक्त करता था एव उसी के प्रसित वह उत्तरदायी होता था। रीस्टाय—विधानमध्या नीम्म सदन—को विधिटत करने का सम्राट को अधिकार था। कभी किसी दल का इस सदन में बहुमत नहीं हुआ था। अत सम्राट वास्तद में सता का स्रोत था।

प्रथम विश्व-पुद्ध म जमनी के पराजित होने पर मिन-राष्ट्रा ने जमनी मे जबारबाद पर आधारित लोकत नीय सस्थाओं की स्थापना का निश्चय किया। 11 जमस्त, 1919 ई को नदीन सबिधान लागू किया गया। इसे वीमर सबिधान (Weimer Constitution) कहते हैं। इस सबिधान द्वारा जमनी म ससदीय प्रणासी की सब्धध्य स्थापना की गयी। 132

बीमर सविधान (1919 ई) के अन्तगत कायपालिका

सविधान के अनुसार राष्ट्रपति मे औपचारिक कायपालिका िमहित थी। वह जनता द्वारा सात बच के लिए प्रत्यक्ष रीति से चुना जाता या एव पुन निर्वाचित हो सकता था। 1919 है से 1933 है के मध्य तक अमनी म दो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए ये—फेडरिक एवट एव माशल हिण्डेनवग। रीस्टाय के दो तिहाई बहुमत द्वारा प्रस्तानित करने पर एव जनता द्वारा उसका समयन करने पर राष्ट्रपति को बापस मी झुनाग जा सकता था। रेकिन ऐसा कोई अवसर कभी उपस्थित नही हुआ। राष्ट्रपति रीस्टाग (Reichstag) का सदस्य नही हो सकता था।

शक्तियाँ

राद्रपति का सविधान द्वारा व्यापक शक्तिया प्रदान की गयी थी। उसे जमन चा सलर की नियुक्त करने एव पदच्युत करने का अधिकार या। यह समीय सना का सर्वोच्च हेनापति था। उसे सम्भे सनिक तथा असनिक अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार या। अत्तर्राद्रीय सम्मेलनो ये वह जमन सप का प्रतिनिधित्व करता या, राजबूतो का स्वागत करता था एव थिदेशा सं समक्रीते एव सिपयौं करता या। विकिन युद्ध एव शान्ति सम्बंधी शक्ति जमन विधानमण्डल को प्रान्त थी। राष्ट्र-पति को क्षमादान की व्यापक शक्ति प्राप्त थी। उसे सन्दक्तान शक्तियाँ में प्रदान की गयी थी। सविधान के अनुसार जमन राष्ट्र की सावजनिक शान्ति एव सुरक्षा हुनु आवश्यकतानुसार उस सवस्त्र सना के प्रयोग तक का अधिकार प्राप्त था। यदि वर्गई पटन

³² Finer op est, p 647

³³ Strong Modern Political Constitutions, p 254

राज्य राष्ट्रीय सिवधान या राष्ट्रीय विधिजनित दायित्वा के सम्पादन मे असफ्त रहता था तो राष्ट्रपति को उस राज्य के विरुद्ध सशस्त्र सेना का प्रयोग करने का अधिकार या ¹⁴ 1919 ई से 1925 ई के धील में जमन राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 48 अर्यात सक्टकालीन यक्ति के अधीन 130 आज्ञान्तिया जारी की थी।

बीमर सिवधान के अधीन राष्ट्रपति नाममान का अध्यक्ष था। मूच (Gooch) के अनुसार, "राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता एव अकुणता का प्रतीक है। वह समारीहों का अध्यक्ष है। सर्वधानिकतन का एक चक्र हे राजनीतिक हिष्ट से वह सूच्य है।" स्कृग के अनुसार, "जमन राष्ट्रपति की स्थिति कास के राष्ट्रपति से सी दयगीन है योगि उस पर दो प्रतिवाध हैं प्रथम, सोकप्रिय निर्वाचन, एव दितीय, असम्बदी के प्रति उत्तरदायी मन्त्रमण्डल।" सविधान के अनुसार जमन राष्ट्रपति के सभी कार्यों का अनुमोदन चा सलर या किसी न किसी मन्त्री के प्रति हस्ताक्षरा (counter signature) द्वारा होना आवश्यक है। चानस्तर या मन्त्री द्वारा प्रतिहस्ताक्षर का यह अध्यक्त किसी के मार्यों के लिए विधिक हष्टि से उत्तरदायी होता या। अं अत जमन राष्ट्रपति मामनात्र का अध्यक्ष था।

मि त्रमण्डल

वीमर सिवधान के अत्तगत मित्रमण्डल यथाय कायपालिका थी। सिवधान के अनुसार चा सलर की निमुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी और उसके परामध से अप्य मित्रमा की निमुक्ति की जाती थी। यात्री पद के लिए विधानमण्डल की सद स्वता अनिवाद मही थी। राष्ट्रपति विधानमण्डल के विक्ता प्रात्म पत्रिमण्डल का ना कर करना था। स्पष्ट है, उपरोक्त वोनो प्रावधान स्वीकृत ब्रिटिश ससदीय प्रणानी के विधारत थे।

जमन मिनमण्डलीय प्रणाली का आधार (1) विवधान (अनुन्धेद 52 त 59 तक), (2) वजट सम्बाधी विधियों (प्रधानत अनुन्धेद 21), एवं (3) गासन की काय-पद्मति एवं आचरण सम्बाधी नियम थे। प्रिनमण्डलीय उत्तरवादित्व की ध्याल्या अनुन्धेद 54 म की गयी थी। चा सतर एवं मिनमण्डल को रीस्टाण का विस्वाध प्राप्त करना आवश्यक था। रीस्टाण के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने पर चा सतर या मिनमण्डल को त्यागपन देना पडता था।

सेक्नि बीमर सविधान भ सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव था । जासतर एव मांत्रमण्डल के सदस्य व्यक्तिगत रूप स तो उत्तरदायी थ, सामूहिक रूप स उत्तरदायी नहीं ने । यह विटिस प्रणाली स एन बत्य महत्वपूष बतार था ।

³⁴ अनुच्छेद 48

³⁵ अनुच्छेद 50

चा सलर अर्थात् प्रधानमानी मिनमण्डल का अध्यक्ष होता था। उसका प्रमुख दायित्व देश की नीति निर्धारित करना था। इसके लिए वह रीस्टाम के प्रति उत्तरदायी था। उसकी स्थिति वहत कुछ ब्रिटिश प्रधानमानी के समान थी।

वीसर सविधान द्वारा समानुपानिक निर्वाचन पद्धित का अनुममन किया गया । अत रीस्टाग म किसी एक दल का बहुमत नही हो पाता था और बहुदलीय पद्धित का विकास हुआ था । 1919 ई से 1933 ई तक 20 मित्रमण्डला का गठन हुआ था । 1919 ई से 1933 ई तक 20 मित्रमण्डला का गठन हुआ था । प्रत्येक मित्रमण्डल का गठन हुआ था । प्रत्येक मित्रमण्डल के तस्य थे । मित्रमण्डल के तस्य निर्वाचन के तिए विदेशी शक्तियों का प्रमान भी उत्तरसाथी हुआ करता था । 1930 ई की विश्वक्यापी मन्दी ने जमन राष्ट्र के मेदरण्ड को ही तोड दिया । वोमर सविधान का अत्य समीप दिखायी देने लगा था । इसके कई कारण थे । इसस प्रमुख थे जननी मे सोकत त्रीय व्यवस्था का अमान, नौकरशाही तथा यायपालिका द्वारा लोकत न के उद्याल आदर्शों को असान, तोकरतात्रीय व्यवस्था का कर सकता, तथा बहुवलीय पद्धित का विकास । राष्ट्रपति सन्य थी अनुच्छेद 48 वह चट्टान प्रमाणित हुआ जिससे टक्टाकर घोमर सविधान चक्नाचूर हो यया । शासन ने इस व्यवस्था के नाम पर 1932 ई तक 233 आवास्तिया (decrees) जारी की थी । 1930 ई के प्रचात जमन सरकार न पूरी तरह सकटकालीन सक्तिया के आधार पर शासन चलाया था। अनुच्छेद 48 जो लोकत न की रक्षा के सिए बनाया गया या, जमनी म अधिनायकत न की स्थापना के तिए प्रमुख रूप वे उत्तरवायी हुआ। यह एक दुर्गाम्यपूण विरोधामास था। य

तीसरे रोक (Reich) का शासन

सीलेसर (Schleicher) के परचात बॉन पपन के परासद्य पर जमन राष्ट्रपति हिण्डेनवा न एडोल्फ हिटलर की चा सलर नियुक्त किया था। उसने 30 जनवरी, 1933 ई को पद प्रहुण किया। स्मरणीय है हिटलर को रीस्टाग म स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं था। 1932 ई (नवस्वर) के चुनावा म नाजी वल रीस्टाग म सबसे बड़ा राज नहीं था। 1932 ई (नवस्वर) के चुनावा म नाजी वल रीस्टाग म सबसे बड़ा राज्य हीते हुए भी उसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं था। हिटलर ने प्वार्क्त होने के परचात राज्य पित हिण्डेनवग को रीस्टाग को विपटित करने एव नवीन चुनावा का आदश देने की तथार कर सिया। निर्वाचन के प्रारम्भ होने के पूव ही रीस्टाग का मवन जला दिया गया। नाजी दल ने इस काय के लिए अपने विरोधी साम्यवादी दल को उत्तर-दायो उहुरामा और विरोधी सल के नेवाला को बची बचा निया गया, प्रेस की स्वतःत्रता सीमित कर दी गयी तथा नागरिक स्वतःत्रता को समाप्त कर दिया गया। परिणामस्वरूप नाजी दल को चुनावा म स्पप्ट बहुमत प्राप्त होने से कोई किटनाई नही हुई। साम्यवादियों को उहोन पृथक रपन का प्रयत्त किया। साब 24, 1933 ई को एक ही बैठक म रीस्टाम से The Enabling Act पारित करान में हिटलर सफल दुआ। इस विषेयक द्वारा शासन को वित्त विषेयका सहित सभी प्रकार के विषयका के

निमाण का अधिकार प्राप्त हो गया या, यते ही इस प्रकार पारित विषेपका का सवयानिक या असवैद्यानिक प्रकृति से ही सम्बाध क्यो न रहा हो। यह विधेपक वीमर सविधान में एक सजोधन मान था। पर तु इस सहोधन ने सविधान को ही समाप्त कर दिया। हिट्टस और उसके मिन्यमण्डल को सभी प्रकार की विधियों पारित करने के अधिकार प्राप्त हो गये। मिन्यमण्डल को रोस्टाग या रीचरेंट (Reuchsiat) की स्वीकृति के विना ही विदेशों से सी धर्मों करने का अधिकार प्राप्त हो गया। यह विधि प्रारम्भ में केवल 4 वस के लिए पारित की गयी थी पर तु इस अधिनयम इरार सीमित नहीं किया गया। हिण्डेनब की 1934 ई म मृत्यु हो गया और इसके बाद हिटलर राष्ट्रपति वन बैठा। वह जीवन मर के लिए राष्ट्रपति नियुक्त किया गया और वह राष्ट्रपति वन बैठा। वह जीवन मर के लिए राष्ट्रपति किया गया और वह राष्ट्रपति वन बैठा। वह जीवन मर के लिए राष्ट्रपति किया गया और वह राष्ट्रपति वन बैठा। वह जीवन मर के लिए राष्ट्रपति करता रहा।

हिटलर जमनी का सर्वेसर्वा वन गया था। उसे Fuhrer कहा जाता था। अपने मिनयों को वह स्वय नियुक्त करता था। वे रीस्टाग के प्रति उत्तरदायों ने होकर उसके प्रति उत्तरदायों ने होकर उसके प्रश्निम्ह कर उसके प्रश्नीमस्य थे। मिन निम्नय के विद्या के प्रति उत्तरदायों होते थे। मिनो उत्तरदायों ने होकर उसके प्रश्नीमस्य थे। मिनम्बर्ग के विद्या के विद्या के प्रति उत्तर के स्वाप्त कर दिया था और वह स्वयम् पुरक्षा एवं विदेश नीति उत्तर्य भी अपने कर तथा था। अपने वह स्वयम् पुरक्षा एवं विदेश नीति उत्तर्य भी अपने कर तथा था। सभी आदेशा पर हिटलर के हस्ताक्षर होते थे, अप मिनयों के प्रतिहत्ताक्षरों का कोई महत्व नहीं था।

हिटलर जमन राज्य व नाजी दल दोना का नेता था। सभी उसी के प्रति
उत्तरवायी थे—वही सत्ता का स्रोत था। उच्चसदन रीवस्टेट (Reichsrat) को 14
फरवरी, 1934 ई को समाप्त कर दिया गया। रीस्टाय (मिम्स सदन) नाजी दल का
गढ वन गया था। जमनी म अनुत्तरवायी शासन व्यवस्था का प्रारम हुआ। हिटलर के
आतक्वादी निरकुछ शासनत व मे नीकरवाही का क्टोर एव पूण नियम्य वा, यायपालिका नियि तत थी एव सवन गुप्तचर पुसिस का साम्राज्य था। इसके अतिरिक्त कर
प्व राज्य म कोई अनत नहीं रह गया था। देश की राजनीति पर नाजी दल का एव
पिवार था। रीस्टाम के निर्वाचन के लिए नाजीदल के हारा एक सूची तथार की जाती
थी। मतदाताओं को केवल इस सूची को स्वीकृत एव अव्यक्ति करते का अधिकार
था। वे अपनी सफलता के सम्ब घ म पूण आदत्तरत रहते थे। नाजी जमनी म नामरिक
स्तात्रता पूणक्षण समाप्त हो गयी थो। यहादियां का कटोरतापूरक दमन किया गया
था। वृद्ध जमन राष्ट्र के निर्माण के लिए अन्तर्रार्थों नित्तनता का बिना किसी

जमनी म हिटलर के उदय के साथ उदारवादी सोकत त्रीय बीमर सिवधान

रफना दिया गया एव नाजी दल द्वारा समिषत हिटलर का अधिनायकत न स्वापित हुआ। हिटलर के समय जमन राज्य को तीसरा रीक (Thud Reich) कहते थे। यह Fubrestat या नेता का राज्य कहा जाता था। नेता की आज्ञाओ का पूण पालन किया जाता था एव नेता ही जनता का पूण एव सबकालिक प्रतिनिधि था। राज्य ही जनता का सच्चा प्रतिनिधि था।

हिटलर की आत्रामक, साम्राज्यवादी, फासिस्टवादी, युद्धप्रिय एव नस्तवादी नीतिमा का स्वामाविक परिणाम द्वितीय विश्व-युद्ध था एव इस विश्व-युद्ध म जमनी निम्न राष्ट्रा से पराजित हो गया था।

द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद जर्मन शासन

जममी ने जून 1945 ई म बिना शत आस्मसमपण कर दिया था। सभुक्त राज्य अमेरिका, कास, सोवियत रूस एव ग्रेट ब्रिटेन के सैनिक नियानण ने जमनी को चार मागा में विमाजित कर दिया गया और चारा राष्ट्रों का जमनी के चार मागा पर पुषक-मुषक अधिकार था। संगुक्त राज्य अभेरिका, कास एव इपलैंड के तीनों सेना मिलाकर स्वतान राज्य के रूप में मा बता दी गयी। इसे परिचमी जमनी का संबीय गणतान (West German Federal Republic) कहते हैं। सोवियत रूस के अधिकार में जमनी का जो माग था वह पूर्वी जमनी या जमन कोकतानीय गणराज्य के रूप म स्वतान राज्य वना दिया गया। हमारे अध्ययन का विषय परिचमी जमनी का संमीय गणराज्य है।

परिचमी जमनी के सिंचधान को मूलभूत विधि (Basic Law) कहत हैं। इसका निर्माण 1948 49 ई मे बोन (Bonn) म आयोजित 65 सदस्यीय ससदीय परिपद (Parliamentary Council) द्वारा हुआ था। यह सदस्य पिक्सी मान के 11 राज्या (Landers) का प्रतिनिधित्व करते थे। तीन वहे राज्यो का प्रमाच सिंचधान पर स्पष्ट है। परिचमी जमनी का बोन सिंचधान निम्म सिद्धान्तो पर आधारित हैं (1) द्विसदमीय व्यवस्थापिका, (2) सीमित कायपालिका, (3) सधीय शासन, (4) यापिक पुनरिक्षण के अधिकार से युक्त निष्पक्ष एव स्वतःत्र यापपालिका। स्पट है, सिंचधान वनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था कि पुन शक्तिशाली के इक्षत निष्कृत शासनत न की स्थापना न हो सके।

वोन का सविधान सितम्बर 1949 ई से लागू हुआ है। सविधान द्वारा सस-दीय प्रणाली की स्थापना की गयी है। कायपालिका के दो बग हैं—राष्ट्रपति एव मित्रमण्डल।

राष्ट्रपति को बीमर सविधान की मौति प्रत्यक्ष रीति से जनता द्वारा निर्वाचित नहीं किया जाता है अपितु एक सवीय सम्मलन म आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आद्यार पर उसका निर्वाचन होता है। सपीय सम्मेलन म निम्न सदन (Bundestag) के सदस्य एव 11 राज्या द्वारा निर्वाचित उतने ही सदस्य भाग लेते है। 🕫 उसका काय काल 5 वप है एव वह एक बार पून निर्वाचित किया जा सकता है। वह नाममात्र का अध्यक्ष है। उसे चा सलर को चुनने का अधिकार प्राप्त है। पर त बु इस्टाग (निम्न सदन) के द्वारा उसके नाम को स्वीकृत किया जाता है। यदि राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित नाम बुडस्टाय को मा य नहीं होता हो राष्ट्रपति पून नाम प्रस्तावित नहीं करता अपितु बु उस्टाग 14 दिन के मीतर अपने कुल सदस्यों के बहुमत से चासनर का

निर्वाचन करता है। यदि किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहमत प्राप्त नहीं होता तो सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को चा सलर नियुक्त कर दिया जाता है। ऐसी अवस्था म राष्ट्रपति को या तो प्रस्तावित नाम को स्वीकार कर लेना चाहिए अथवा बु उस्टाग को विघटित करके नवीन निर्वाचन का आदेश देना चाहिए । राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर पदच्युत किया जा सकता है। 37 उसे रक्षित (Reserved) शक्तिया भी प्राप्त है।38

वोन सविधान में संघीय मित्रमण्डल की भी व्यवस्था है । उसका प्रमुख चा सलर या प्रधानमात्री होता है। वीमर सविधान की अपेक्षा चा सलर की शक्तियाँ अधिक है। यह अब अधिक शक्तिशाली है। सामायत चासलरका कायकाल 4 वर्ष होता है। प्रधानम त्री को उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर अप

36 यदि दिलीय मतदान के पश्चात भी किसी प्रत्याशी को पूम बहुमत प्राप्त नहीं होता

तो तीसरे मतदान में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याची को राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। अवधि के पूर्व राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने पर संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन (Bundestag) के अध्यक्ष द्वारा उसके दायित्वा को सम्पादित किया जाता है। 37 जानवूमुकर सविधान का उल्लंघन करने पर सवैधानिक यायालय के समक्ष राष्ट्रपति के विरुद्ध कायवाही की जा सकती है। महानियोग प्रस्ताव पर तमी विचार किया जा सकता है जबकि दोनो सदनो के कम से कम एक चौबाई सदस्य उसके पक्ष म मत देते है एव दोनो सदना के दो तिहाई सदस्यों का बहुमत पृथक पृथक रूप म प्रस्ताव को समयन करे। सवधानिक यायालय द्वारा राष्ट्रपति की

वीपी पान पर उसे जपदस्थ किया जा सकता है। 38 राष्ट्रपति को निम्न रक्षित शक्तिया प्राप्त हैं (अ) रीस्टाग का अधिवेशन न होने की स्थिति म चा सत्तर के प्रति हस्ताक्षर से

यद्ध की घोषणा करना। (आ) चासलर को बहुमत स निर्वाचित करने की दशा म रीस्टाग को विष टित करना ।

⁽इ) चा सलर का नाम प्रस्तावित करना। (ई) सपीय सरकार की प्राथना पर सबधानिक सकट की घोषणा एव निम्न सदन ना विघटन करना ।

दस्य किया जा सकता है। अविद्वास के प्रस्ताव म उत्तराधिकार का उल्लेस होता है तथा प्रस्ताव उपस्थित करन के कम से कम 48 घण्टे पद्वात उसका नाम प्रस्तावित कर दिया जाता ह। यह प्रस्ताव निम्न सदन के कुल सदस्या के स्मय्ट बहुमत से पारित होना वाहिए। एसी स्थित म पुराना चान्सवर सुरत अपदस्य हो जाता है एव नवीन प्रधानमधी को उसके स्थान पर नियुक्त कर दिया जाता है। यदि पुराने चा सतर को रीस्टान के आधे से कम सदस्या का समयन प्राप्त होता है तो वह राष्ट्रपति को रीस्टान के आधे से कम सदस्या का समयन प्राप्त होता है तो वह राष्ट्रपति को रीस्टान को विचटित करने का परामदा दे सकता है। क्ष्य स्थान से दौरान जो मित्रमण्डलीय अस्थितत पी उसे इस ब्यवस्या से दूर करने का प्रयत्न किया गया है।

ब्यवहार म चासलर ही मित्रमण्डल के सदस्यों को चुनता और पदच्युत करता है। प्रयम राष्ट्रपति एडिंग-गार (Adenauer) ने अनेक बार मित्रमण्डल से बिना पूछे अनेक महत्वपूण निषय लिये थे। मित्रमण्डल के सदस्यों को दोना सदना की प्राथमा पर जनकी बठका म माग लेने का अधिकार है। पर तु अधिकास मात्री सहना की बैठकों स अनुपरिचय ही रहते हैं।

राष्ट्रपति की सभी भागाप्तियो एव आदेशा पर वासनर या अय सम्बधित सपीय मित्रयो के प्रति हस्ताक्षर होते हैं। इसके केवल तीन अपवाद हैं (1) चास लर को नियुक्त करने एव पदच्युत करन सम्बधी आदेश, (2) शु इस्टाग हारा चास- लर को बहुमत स निवधित करने म असफल रहने पर सदन को विघटित करने सम्बधी आदेश, एव (3) कायकारी चासनर एव मित्रमण्डल को नये उत्तराधिकारो की निवक्ति तक कार्य करने सम्बधी आदेश, एव (व) कायकारी चासनर एव मित्रमण्डल को नये उत्तराधिकारो की निवक्ति तक कार्य करने सम्बधी आदेश।

चासलर यथाय कायपालिका है एव राष्ट्रपति नाममान की कायपालिका है। चासलर देश की नीति को निर्धारित करता है, युद्ध एव युद्धजनित सकटकाल की घोषणा करता है, सेनाओ पर उसका नियानण होता है, सुरक्षा मानी शातिकाल म सर्वाच्च सनापति होता है तथा वह प्रधानमानी के अधीन होता है। युद्धकाल म सभी मेनाओं की कमान चा सतर के हाथा में होती है। वह सधीय मानिमण्डल के सदस्यों म विभागों का वितरण करता है तथा मानिमण्डल का गठन करता है। चासतर का पद राष्ट्रपति की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है।

पश्चिमी जमनी म कायपालिका को रोस्टाग के प्रति उत्तरदायी एव राष्ट्रपति को नाममान का अध्यक्ष बनाकर तथा मिनिया को उसके कार्यों के सम्बाध म प्रति हस्ताक्षर के अधिकार देकर निस्सादेह ससदीय श्वासन प्रणाली की स्थापना की गयी है।

सोवियत कार्यपालिका [SOVIET EXECUTIVE]

सोवियत रूस की सर्वोच्च कायपालिका एव प्रशासनिक अग मिन-परिपद

(Ministry) है। 10 मार्च 1946 ई के पूर्व तक इसे काउनसल ऑफ दी पीपुल्स कमी मार (Council of the Peoples Commissars) के नाम से पुकारा जाता था। उसके परचात मिन-पिरपद को काउ सल ऑफ मिनिस्टस (Council of Ministers) की सजा दी गयी है।

स्टालिन सविधान के अनुसार मित्र-परिषद सोवियत रूस की सरकार है। (अनुच्छेद 56)

रचना एव सगठन

कस म मिन-परिषद सर्वोच्च सोवियत के दोनो सदना-मोवियत जॉफ प्रमिपन एव सोवियत ऑफ नेशनस्टीज—की सयुक्त बैठक म चुनी जाती है। यदि सर्वोच्च सोवियत का अधिवेशन न हो रहा हो तो सोवियत क्स की प्रेसीव्यिम को मिन-परि पद के अध्यक्ष अधात प्रधानमनी की सिफारिश पर मिन्यों को नियुक्त एव पदब्युत करने तथा मनात्या को समाप्त करने या उनका पुनगठन करने की शिक्त प्राया है। जिकन प्रेसीव्यिम के द्वारा किये जाने वाले कार्यों का बाद म सर्वोच्च सोवियत द्वारा अनुमोदिन किया जाना आवश्यक होता है। मिन्य परिषद सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके सनावसान काल में वह प्रेसीव्यम के प्रति उत्तरदायी होती है।

प्रधानम नी मिन-परिपद का अध्यक्ष होता है। प्रधानम नी के अतिरिक्त एक विरुट उप प्रधान, उप प्रधान राज्य नियोजन आयोग का अध्यक्ष, सोवियत नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष, स्टेट वक वीड का अध्यक्ष, कता समिति, उच्च विक्षा सम्ब भी समिति, निर्माण काथ समिति के अध्यक्षगण एव मनीणण मिन परिपद के सदस्य होत हैं। हिं (अनुच्छेद 70)। निन परिपद की सदस्य सस्य समय समय पर बदलती रही है। 1924 हैं में इतकी सदस्य-सस्या 10, 1936 हैं में 32, 1947 हैं में 59, 1950 हैं ने 31, 1955 हैं में 59 एवं 1952 हैं में 69 वी। स्टालिन की मृत्यु के समय

पुनगठित मित्र परिपद की सदस्य-सस्या 30 थी।

सोवियत रस में दो प्रकार के मजात्वय हूँ—अखिल सपीय मंत्रालय (All Union Ministries), एवं सम गणराज्यीय मन्त्रालय (Union Republic Ministries)। अलिल सपीय मंत्रालया का सम्बाध सधीय विषया सहोता है एवं इनको सोत्राधिनार देशव्याची होता है। इनकी सम्बा 1950 ई म 30 निष्कृत कर दो गयों भी। सम गणराज्यीय मंत्रालया का सम्बाध सामा य क्षेत्र ने ऐस विषयों सहोता है जिन पर राष्ट्रीय सरकार एवं साम की घटन इनाइयो—सम मणराज्य ने सरदाय—मंत्रा सुधक संत्राधिनार प्रकार होता है। इत्या प्रमाणक विषया प्रणाणक सम्बीधित मंत्रालयों के इत्या स्वामायों के इत्या निया जाता है। यह अंतर सदय मुनिष्कृत नहीं हाता। अनव

⁴⁰ Article 79

मात्रालया को एक स दूसर बंग में हस्ता तरित किया जाता रहा है। मुनरों ने दोना के अतर यो स्पष्ट करत हुए वहा है कि अखिल संधीय मात्रालया का प्रशासन रूस की राजधानी मास्को म वेजित है जबकि सब गणराज्यीय मात्रालया मा प्रशासकीय कार्यों वा निय त्रण केजित है लियन किया वयन बहुत सीमा तक विकेजित होता है।

अखिल सघीय म त्रालयों की सस्या प्रारम्भ म केवल 5 थी। 1936 ई में स्टालिन सविधान के जंतगत 8, 1942 इ. म. 13, एव. 1947 ई. म. 36 थी। 1950 ई. म. इनवी सस्या 50 निश्चित कर थी गयी। (अनुच्छेद 77)

प्रमुख अखिल संघीय म नालय निम्नत हैं

विदस व्यापार, कामज एव लकडी उचीम, संस, मोटर, ट्रेक्टर, एव वायुयान उचीम नीसेना, शस्त्रास्त्र, रंस, कृषि-यन्त्र, यातायात, सोहा एव इस्पात उचाम, कोमला रसायन, विजली उचाम आदि।

प्रमुख सध गणराज्यीय म त्रालय निम्न हैं (अनुच्छेद 78)

आत्तरिक मामले, सेना, उच्च विक्षा, सावजनिक स्वास्थ्य, बैदेशिक मामले, वन-सम्पदा कृपि, व्यापार, वित्त, याय, खाद्य उद्योग, लघु उद्योग आदि ।

भागालया की सत्या म बिंद ने नारण एक प्रकार के आन्तरिक मिनमण्डल (Inner Cabinet) का निकास हुना है। मिनमण्डल का अध्यक्ष अयाँत प्रधानमन्त्री एव उपाध्यक्ष आ तरिक मिनमण्डल के सदस्य होते हैं। इसके द्वारा मिन-परिपद के विनिन्न मानालया के कार्यों का निरीक्षण एव आवश्यक समय्य किया जाता है। आतरिक मिन-परिपद के सदस्य सामायत साम्यवादी दल के प्रमुख नेता एव दक्षीय प्रेसीडियम के सदस्य होते हैं। दतीय प्रेसीडियम देश की नीति निर्माण करम वाली प्रमुख सस्या है। जत आतरिक मिनमण्डल दल एव सासन को जोडने वाली एक कडी की माति है।

शक्तियाँ

मित परिषद की शक्तिया निम्नवत ह

- (1) सभी अखिल सधीय एवं सघ गणराज्यीय म त्रालयो एवं सधीय शासम की अन्य सस्याओं के कार्यों का निर्देशन एवं समान्य करना।
- (2) राज्य के आय व्यय विवरण एव राष्ट्रीय आर्थिक विकास योजना कां तैयार करना तथा उसके निया वयन हेतु उचित एव आवस्यक व्यवस्था करना।
- (3) सावजनिक व्यवस्था एवं देश की सुरक्षा तथा नागरिक अधिकारो एव राज्य के हितो की रक्षा।
 - (4) वदेशिक म त्रालया का प्रवाध।
- (5) सुरक्षा हुतु वार्षिक सिनक सेवा एव देस की सेना के सामा य सगठन की व्यवस्था करना। सधीय म"त्रालय अनुक्क्षेद्र 66 के अधीन पारित विधियो के

आधार पर निषय एव बादेश जारी करते है एव विधिया के किया वयन का निरीक्षण करते है।

(6) सुरक्षा, सास्कृतिक एव आधिक कार्यों के सम्पादन हेतु समय समय पर विदोष समितिया एव के द्रीय प्रशासन की स्थापना करना । (अनुच्छेद 68)

(?) अपने अधिकार क्षेत्र के अत्वात मिन्न-परिषद की संघीय गणराज्यीय मित्रयो एव संघीय मित्रया के निणयो एव आदशा को निलम्बित करने का अधिकार प्राप्त है। (अनुच्छेद 69)

(8) संघीय मीं त्रया को राज्य के प्रशासन को निर्देशित करने का अधिकार है (अनुच्छेद 72 एवं 75)। अनुच्छेद 76 के अधीन संघीय मीं त्रयों को राज्य प्रशासन को सम्बन्धित संघ गणराज्यीय मंत्रालया के माध्यम सं निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है।

(9) सधीय मिनयों को अपने क्षेत्राधिकार के अन्तगत मीन परिषद के निणमा को त्रिमाचित करने के अधिकार भी प्राप्त है। (अनुच्छेद 76)

वया सोवियत मित्र परिषद ससदीय प्रणाली का उदाहरण है ?

सीवियत मिन परिपद को अन्य ससदीय प्रणालियो वाले देशों की माति
'Council of Ministers' की सना दो जाती है। वे सुप्रीम मोदियत के सदस्य होते हैं एव जसी के प्रति अपने कार्यों एक नीतियों के सिए उत्तरदायी होते हैं। पुप्रीम सोवियत के सनायसान काल म वे प्रेसीहियम के प्रति उत्तरदायी होते हैं (अडुक्टेंट्र' 65)। सुप्रीम सोवियत के सदस्य मिन परिपद से प्रदम पुद्धते हैं एव उनका उत्तरी होते हैं (अडुक्टेंट्र' किए दोना अतिवाय होता है। सोवियत या लिखित रूप में तीन दिन म मिन्या के लिए दोना अतिवाय होता है। सोवियत मिन परिपद के सभी सदस्य एक हो राजनीतिक विचारभारा के होते हैं। बद्ध व्यवस्था स्वत हो एव जिलावायता है व्यक्ति सोवियत स्तम में केवल साम्यवादी वर्त
का ही अस्तित्व है। सोवियत मिन परिपद के अध्यक्ष को प्रधानम प्री गहते हैं।

सीवियत प्रधानमानी की स्थिति इस स सर्वाच्च है। स्तातिन, मेनिनकोव, वुलगानिन तथा खूबचेव जैसे प्रभावधाली व्यक्तित्वा न इस पव को सुपीनित किया है। सामायत दल म प्रधानमानी की स्थिति ने प्रीय होती है। वत वह अनय प्रकारिय प्रधानमानी की स्थिति ने प्रीय होती है। वत वह अनय प्रकारिय प्रधानमानी हो। लेकिन सोवियत सम के प्रधानमानी की स्थिति उसके व्यक्तित्व पर निमर करती है। निमी भी प्रधानमानी नो इस उच्च स्थिति से यरवस हटना मी पढता है। उदाहरणाय, 1924 स 1930 ई तक रिकोव (Rekov) कस ना प्रधानमानी था लेकिन 1938 ई म दशहोह का आरोप तयाकर उस परच्युत कर दिया गया।

साविवत मिन्न-परिपद की उपरोक्त सभी व्यवस्थाएँ ससदीय व्यवस्थापिना की बाइतीय विभेपताओ को पूण करती हैं। अत बाहा रूप स एसा लगता है कि रूम म ससदीय नायपालिका है। तेक्नि आलोचना का यह मत है कि रूस की मिन्न-परिपद ससदीय कायपालिका का उदाहरण नहीं मानी जा सकती । इस कथन के पक्ष में निम्न तक प्रस्तुत कियं जाते हैं

- (1) सोवियत रूस म एक दलीय व्यवस्था है। साम्यवादी दल एकमान दल है। एकदलीय व्यवस्था म मित्र परिपद का निर्माण पूच निश्चित तथ्य है। सोवियत रूस मे मित्र-मरिपद का निर्माण बहुमत दल के नेता द्वारा नहीं किया जाता अपितु साम्यवादी दल की मेसीडियम द्वारा मित्रयों की सूची तथार की जाती है। मित्र-परिपद सिद्धात रूप में सुधी स्वार परिपद है। हिस्स में प्रति उत्तरदायी होती है। सोवियत एक्स में क्यी निष्य दलीय स्तर पर निये जाते हैं एव व्यवस्थापिका तथा कायशालिका उह अनुमोदित मान करती हैं।
- (2) प्रधानम नी ससदीय दल द्वारा नही चुना जाता है। उसकी दुलना हम ससदीय शासन प्रणाली के प्रधानम नी से नहीं कर सकते। इगलण्ड का प्रधानम नी से नहीं कर सकते। इगलण्ड का प्रधानम नी से नहीं कर सकते। इगलण्ड का प्रधानम नी से निवास ते काम स समा में अपने दल का नेता होता है। लेकिन सावियत प्रधानम नी के लिए यह आवस्यक नहीं कि वह सोवियत आफ दी यूनियन में अपने दल का निता हो। स्टालिन का दल एव धासन दोना पर एकाधिकार था। उसकी मत्यु के पत्रवात मेलिनकोव व बुलगानिन साम्यवादी दल के उसी के समान असदिग्ध नेता नहीं थे।
- (3) विरोधी दल का अस्तित्व ससदीय प्रणाली की अनिवाय विशेषता है। लेकिन कस मे एकदलीय व्यवस्था के कारण विरोधी दल का वहा पुण अमान है।
- (4) सुप्रीम सोवियत के सदस्या को मित्रयों से प्रश्न पूछने के अधिकार प्राप्त है। लेकिन म नीमण केवल सुवना मात्र देते है। अविश्वास के प्रस्ताव का साम्यवादी दल के फीलादी अनुशासन के कारण पारित होना एवं वकल्पिक सरकार का निर्माण निवा त असम्मव है।

स्ट्राग के अनुसार सोवियत गिन परिषद सवैधानिक कायपालिका नहीं है, फलस्वर पह ससदीय न होकर असदविय कायपालिका है। 11 1936 ई के दर्शान्त सविधान (1947 ई में सवोधित) के अनुसार राज्य शक्ति का सर्वोच्च अग पू एक एस आर की सुनीम सोवियत है (अनुच्छेद 30)। लेकिन मुग्नेम सोवियत वी मेंसी- डियम को उसके सानासान-काल म आदेश जारी करके विधि निर्माण वा अधिवार प्राप्त है। सोवियत स्स की गिन-परिषद राज्य शक्ति का सर्वोच्च अग है (अनुच्छेद 64)। प्रति परिषद सुनीम सोवियत हारा अपने सपुक्त अधिदेशन म नियुक्त की ताती है अरे सुनीम सोवियत के प्रति हो उत्तरदायो होती है एव सानासान-वाल म प्रेसीडियम के प्रति । लेकिन तथ्य यह है कि मीन परिषद के याय कायपालिका तक ही सोमित नहीं हैं। वह आदेश द्वारा विधि निर्माण कर सकती है। हर स्थित म दोना

⁴¹ Strong Modern Political Constitutions, pp 260-61

मस्याभः —प्रेमीटियम एव या व परिषद —को माम्यवादी दन की के द्रीय समिति क सहयाग से बाय करना पहला है। इसका आधिक कारण, जैसा कि स्टालित ने स्वय कहा है, यह है कि सवहारा का अधितायकृत्व यथाय म साम्यवादी दल का अबि नायकृत्व है और दल मबहारा का मायहुगन करता है।

फाइनर वं अनुसार मोजियत कायपालिका प्रयासी म एक प्रकार वो इपता (duality) पायो जातो है। नायपालिका के काय प्रेसीडियम एव मन्त्रि परियर (Council of Ministers) में विमाजित है। प्रेसीडियम वा मिजिय सिंहत समी पदा निजारिया के मुप्रीम सावियत व मजासमान-काल म नियुक्त एव पदच्युत करन की राक्तिया प्राप्त है। वेचन जीपचारिक स्वीकृति को छोडकर मिजियरिय का महन एव उत्तरा निय त्रण मी प्रसादियम कहाया महाता है। मित्र परिषद ही मिजियरब (Cabinet) है। इनके भाष्ट्रिक उद्वाद हो परत्तु मंत्री अपने विधियर विमाजी है कि प्रमादियम काउ सन प्रचारी होने है। सवाधिक महत्वपूण बात यह है कि प्रमीत्यम काउ सन एव साम्यवादी दल की पोलिडभूरी अंग्रह सम उत्तर प्रमाद में साम स्वाप्त का साम्यवादी वस की पोलिडभूरी अंग्रह सम उत्तर प्रमाद साम स्वाप्त का उत्तर प्रसाद साम उत्तर प्रमाद सम्बद्ध साम स्वाप्त का उत्तर प्रमाद सम्बद्ध साम स्वाप्त सम्बद्ध साम स्वाप्त सम्बद्ध सम

भुनरो न निस्न शक्ष्ण म मोवियन परिपद के सम्बाध म विचार प्रस्तुत किय है जया वास्तव म कम य नवीन सविधान द्वारा मिनमण्डलीय उत्तरदायित के सिद्धात पर आंशांन्य उत्तरनायों गासन की क्यापना की गयी है ? इनका तकमगत उत्तर ना सकारास्मक हो हा सकता है। मिन परिपद मर्बोच्च सोवियत द्वारा नियुक्त गांव उसी क प्रति उत्तरदायों होती है। वागज पर सावियत एव कच मिनण्डला में मिन परिपद मर्वोच्च उत्तरहायों होती है। वागज पर सावियत एव कच मिनण्डला में मिन परिपद में वहुँ व अतर है। सावियत मानीभा ध्यवस्थापिक समाति होते हैं। वेशे साव्य वादी मल की राजनीतिक समिति द्वारा नियंचित होते हैं और राजनीतिक समिति क्ष स महासचिव द्वारा नियुक्त की जाती है। सिद्धास्तत वे सर्वोच्च सावियत एव प्रेसी डिपम क प्रति उत्तरतायों होने हैं। कोई भी मानी प्यास्थ दहता है पर पद से पृपक हाता है यह उस मानी के दिलीय नेताआ न कि ससदीय नेताओं के साथ मन्य पा पर नियर परता है।

सीवियत रूस की सर्वोच्च सोवियत की प्रेसीडियम

प्रेमीडियम मीवियत रूस के सविधान की अनीक्षी मस्या है। सर्वोच्च सीवियत (Supreme Soviet) के दोनो मरना की समुक्त बठक में इसका चुनाक किया जाता है। प्रारम्म म प्रमीडियम य एक अध्यक्ष (Chautman) 16 उपाध्यक्ष (Vice

⁴² Finer op at pp 666 67

¹³ Munro Governments of Europe, pp 748 49

Chairman) होते थे। प्रत्येक सघ गणराज्य में से एक अध्यक्ष चुना जाता था। इसके अतिरिक्त 24 अतिरिक्त सदस्य भी होते थे । 1946 ई मे अतिरिक्त सदस्यों की सरया घटाकर 16 कर दी गयी है। इस प्रकार इसकी कुल सदस्य सरया 33 थी परत् 1966 ई मे इसकी सदस्य सख्या को बढाकर 37 कर दिया गया है, जिसमे एक अध्यक्ष. 15 गणराज्या के प्रतिनिधि के रूप मे 15 तपाध्यक्ष (Vice Presidents) तथा 20 साधारण सदस्य होते है । 1919 ई से 1946 ई तक प्रेसीडियम के अध्यक्ष एम आई कालिनिन (M I Kaima) थे। उसके पश्चात एन एम शिवरीनक (N M Shverink) के बारोशिलोब (K Voroshilov) एव मिकोयान (Mikoyan) कमश अध्यक्ष रहे । प्रेसीडियम के सदस्य सर्वाच्च सोवियत के सदस्य (Deputies) होत हैं। प्रेसीडियम सिद्धा तत अपन कार्यों के लिए सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तर-दायी होती है।

प्रेसीडियम का सामा य कायकाल 4 वप है। लेकिन सुप्रीम सोवियत के अन्ते कायकाल स पूत्र ही विघटित होने पर प्रेसीडियम भी उसी के साथ विघटित हो जाती है । पुरानी प्रेसीडियम उस समय तक काय करती रहती है जब तक कि न्यान सुप्रीम सोवियत का निर्वाचन नहीं हो जाता । नवीन सुप्रीम सावियत हा हक नुसर्ना प्रसीडियम के द्वारा निर्वाचन के तीन माह के भीतर बुलाया जाता है (यून्ट्रेंट 55)। सुप्रीम सोवियत के निर्वाचन सम्बाधी आदेश उसके कायका र की सनास्टिया विरटन के दो माह के भीतर प्रेसीडियम द्वारा ही जारी किय जात हैं।

मोवियत रूस म सर्वोच्च सोवियत राज्य प्रक्ति का सर्वोच्च उस है। दें। क शासन का समस्त दायित्व उसी पर होता है । सर्वे च्च साविष्ट के होनी सदना का आकार वृहद है। जनकी सदस्य सख्या बहुत अभिक्र है। कि वर्ड के उनके केवन दो ही सब हाते हैं। प्रत्येक सब का कायकाल सामा यह 10-12 दिन होता ह जा उसक दायित्व को देखते हुए निश्चय ही अपयाप्त है। यक 🎏 किए की आवस्यकता अनुमन करना स्वामाविक या जा सुप्रीम सावित्त हु मुक्क मान काल म उसके दादिन्ती को सम्पादित कर सके। फलत प्रेसीटियम की न्यास्त्र की बारी । प्रेमीटियम सर्वेक्स सोवियत की एक स्थायी समिति है जिनक अधिकार जिल्ला होता हुने हैं जा वी सुप्रीम सोवियत के दायित्वा का उसके नव उसके नव उसके के नाम के नाम के अय दनिक कार्यों को भी करती है।

प्रेसीडियम की शक्तियाँ

सविषान द्वारा प्रेसान्दिन का जानक जानक (स्टुन्टेंट न्ष्ट) जान के 🖰 है। वे निम्नत ह

⁽¹⁾ सर्वोच्च सावित्र के क्रीट्रक्ती के क्रांट्र क्रमा इस्कार्क

⁴⁴ अनुच्छेद 48

के होना सदना म मनभा होने को स्थिति म उसे भग करके नव नियायन को आहे. होता ।

- (2) जागानिको जारा बरता गाविवत गय को प्रचित्त विधिया की व्याक्य हरता नथा गर्वीय मी च परियट जयवा किसी गणराज्य व मविधान विरोधी निमया गय जाल्या हा जस्वीरन करता ।
- (3) स्वच्या या रिमा श्रामण्य द्वारा मीग रहा पर जनमत-मग्रह को व्यवस्था करता लिंग जाज नग माविया स्था म नाइ जनमन-मग्री महा हुआ है।

(4) मुत्रीम माविष्टा ४ तत्रावमान-तान न प्रामीदिवम को प्रामित्राहरू सदस्या तो नियुक्त एव पदच्युन वरण का अधिकार प्राप्त है। नवीन मात्रालया के निमाण एव उनका ममाध्या गया नवीन गत्राक्ष किमाण एव विद्यमान क्षत्रा मध्यवस्था

और मुधार करन मध्याधी अधिकार मा प्रेसीक्षियम को प्राप्त हैं। लेकिन इते सब वार्यों का सर्वाच्य मात्रिया ग्राम अनुमादन वावस्यक है। (5) मुखीम साजियत क समावसाजनाल स बाह्य वाक्सण या किसी वन्त

राष्ट्रीय मिप र दायित्वा का पूनि के लिए युद्ध की पायवा करने का अधिकार प्रेषी-रियम का प्राप्त है। मना र उच्च पर्शायकारिया का नियुक्त एव वहच्युन करने, सना स एच्छिक एव अनिवाद मनी सम्ब था क्षत्रीय या दशस्याची आदेश कारी करने, सनिक कान्त (Martisl Law) का पायवा करने तथा सनिक यायासमा की स्थापना

र भी अधिकार प्रसीक्षियम का प्राप्त है। (6) प्रेमीडियम अन्तराष्ट्रीय सचिया का स्वीकृत एवं अन्वीकृत करती है।

वह दूसरे देशा म राजदूता की नियुक्ति करती है एवं विदेशी राजदूता का स्वागत करती है।

(7) प्रसीडियम द्वारा सनिक उपाधियो, राजनयक पद एवं जाय सम्मानसूचक

एवं विशेष उपाधियाँ प्रदान की जाती हैं। उसे धमादान के भी अधिकार हैं।
(8) सुत्रीम सावियत के सदस्या का बादी बनान के विरुद्ध उ मुहित्यों
(immunity) प्राप्त हैं। सुत्रीम सावियत की सहमति या उसके समावसान-कात म मेसीदियम की सहमति से ही व बादी बनाय जा सकते हैं।

प्रेसीडियम का अध्यक्ष

ेसीडियम का अध्यक्ष ही सोवियत सथ का अध्यक्ष होता है। वह राज्य के अध्यक्ष के दाधिक एव नायों को सम्पादित करता है, यद्यपि सविद्यान या मुश्रीम सावि यत का निसी विधि ने हारा उसे ये दाधिक अदान नही किया गये हैं। वह सर्वोच्च सावियत द्वारा पोधित विधियों एक प्रेसीडियम के आदात्रों पर हस्ताक्षर करके उनकी पोपणा करता है। वह प्रेसीडियम के अध्यक्ष के असे मम्पादित करता है यद्यपि

ऐसा कोई सर्वधानिक उपवाध नहीं है । उदाहरण के लिए, वह विदेगी राजदूता एव राजनयना का स्वागत करता है एवं अन्य राज्याच्यक्षों के साथ संघानता के स्तर पर स देशा का आदान प्रदान करता है। प्रेसीडियम ना अध्यक्ष एक प्रकार स राज्य का नाममात्र का अध्यक्ष होता है। उसके पद का औपचारिक महत्व है, राजनीतिक नहीं। मादर में अनुसार उसका प्रमुख काय अय देशा के राज्याध्यक्षा की मीति सामा य नागरिका ॥ सम्यक रपना है। जन हित में यह शासन का पितृ-तुत्य सजीव मानवीय सम्बन्धा का प्रकार मात्र है। प्रेसीडियम की यसाय किपति

प्रेसीडियम वा सावियत रूप वी शासन व्यवस्था म महत्वपूण स्थान है। उस विधायी एव कायपालय अधिकार प्राप्त हैं। प्रेसीडियम का अध्यक्ष राज्याच्यक्ष के द्वार ओपचारिक मतस्था को निमाता है। उसके कुछ काय यायिक भी है। रस म यायिक पुनर्रिक्षण (Judicial Review) वो श्रांक यायपालिका को प्राप्त नहीं है। मेसीडियम को सण एव राज्या के सविधान विरोधी आदेश को अवैच भाषित करने एव विधिया की ब्याच्या करने का अधिकार है। अत प्रेसीडियम उन कतच्या को सम्मादित करती है जा लोकत त्रीय देशों म यायपालिका द्वारा किये जाते हैं। सभीय प्राप्तन एव पटक शासान के मध्य उत्पान विवादा के निपदाने का अधिकार अय अधीय रात्त एव पटक शासान के मध्य उत्पान विवादा के निपदाने का अधिकार अय अधीय रात्त एव पटक शासान के मध्य उत्पान विवादा के निपदाने का अधिकार अय प्राप्त प्रयाम प्रवाम प्रयाम प्रयाम प्रयाम प्रवाम प्रयाम पर केवल यही प्रतिवाध है कि सर्वोच्च सोवियत द्वारा इन कार्यों का अनुमोदन हाना चाहिए। लेकिन यह औपचारिक व्यवस्था मात्र है। इस स सास्यवादी दल एकमान दल है एव उसके फोलादी अनुसासन के कारण प्रेसीडियम की स्थित केत्रीय है। अत व्यवहार में प्रेसीडियम सोवियत रूस के सविधान का मुख्य व्यास्थाकार (interpreter) एव सरका है।

प्रेसीडियम की स्थिति के सम्ब ध म बिहाना म तीव मतभेद है। प्रस्त यह है कि क्या प्रेसीटियम को सावियत क्या है ? मुनरो प्रेसीडियम को क्या स्थारियम की वास्तविक स्थित क्या है ? मुनरो प्रेसीडियम को क्या की शौपपारिक कायपासिका नहीं मानत । उनके अनुसार सोवियत क्या विना अध्यक्ष का स्था है । इपले के सावि प्रति कर्या की स्था की सावि वहीं कोई अध्यक्ष नहां है। सुनरो के घवदा म, '1936 ई के सविधान द्वारा सोवियत क्स म अध्यक्ष की यवस्था नहीं की गयी है।' प्रेसी डियम एव इगलण्ड के राजा की तुलना करना प्रासमिक होगा। ब्रिटिश राजा का पद वदा परप्परागत है और वह जीवनथ्य त पदाक्ष द एहता है। इसके विपरीत, प्रेसीडियम केवस 4 वप के लिए निर्वाचित क्यु समिति है जीर अपने कायों के लिए सुप्रीम सोवियत के प्रति उत्तरदायी होती है। इसकेया ना प्रमान का अध्यक्ष है एव उसके नाम पर किये जाने वाले कायों के लिए सिनमण्डल ब्रिटिश ससद है एवं उसके नाम पर किये जाने वाले कायों के लिए सिनमण्डल ब्रिटिश ससद के प्रति

⁴⁵ Carter, Renny & Hez The Government of Soviet Union, 1954, p 1

प्रेमीडियम एव अमेरिकी राष्ट्रपति म कायनाल की समानता है। दोना म शय सभी असमानतार्गे हैं । अमेरिकी राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित हैं, भैसीडियम मुत्रीम मोवियत द्वारा । व्ययस्कि गष्टपित कविस कं प्रति उत्तरदायी नहीं है, जबकि प्रेसीन्यम मुप्रीम मोवियत कं प्रति उत्तरदायी होती हैं। स्पट्ट है कि सावियत इस की शामन प्रवासी शक्ति पृत्रकरण पर आधारित नहीं है, वहाँ सिद्धा तत इंगलैण्ड की मीति ससद— मुत्रीम मावियन—की सम्प्रमृता है। अमरिका का राष्ट्रपति इगलैण्ड क राजा की मानि एक्स कायपानिका का उदाहरण है, प्रेसीडियम एवं सामूहिक सस्या है।

मुनरों के मन के विपरीन हायर एवं धामसन उन विचारका म हैं जो प्रेसी-डियम का नियमित कायपालिका स्वीकारत हैं। उनके अनुसार, प्रेसीडियम उसी रूप म (बहुल) कायपालिका है जिस रूप म फास का राष्ट्रपति या इंगलण्ड का राजा शय पालिका है। अविन हायर का उपराक्त कथन माथ नहीं है। रूस के सविधान म मि नमण्डन का अस्तित्व है एवं मित्र परिपद सुप्रीम सोवियत और उसके सत्रावसान काल म प्रसीन्यिम क प्रति उत्तरत्यथी होती है। उससे हापर के मत की गम्मीरता समाप्त हो जाती है और मुननो व मत वा समयन हाता है।

प्रभीच्यिम की स्थिति सम्बाधी जपरोक्त दोनो मत अतिस्थोक्तिपूण हैं। प्रेसी डियम को लघ सच्या एवं उस प्राप्त शक्तिया के कारण उसका विशेष महत्व है एव मिनमण्डल के समान ही दश ने जासनत न में उसकी स्थिति कादीय है। हम की प्रेसीडियम की पूनवर्ती दलीय कंडीय नायपालका समिति (C E C) के समकक्ष मान सकत है। यह उसकी सातान है। फाइनर ने सावियत रूस की प्रेसीडियम की विधि एव व्यवहार में सतत सरकार की सज्ञा दी है। अविधि निर्माण की युपाय शक्ति तथा यित्रमण्डल को नियनित क्यन की पूण सक्ति प्रसीडियम म निहित है। एक द्वसर स्थान पर काइनर प्रेसीडियम को दल एव राज्य का वानावाना मानना है। प्रतिनियम के सभी सदस्य साम्यवादी दल के सदस्य होते है। अत साम्यवादी दल एव सीवियत शासन म प्रेसीडियम कं माध्यम स समावय हो सका है। विशिक्तको कं अनुसार, प्रसीडियम सामूहिक राष्ट्रपति है। पूजीवादी देशी के राष्ट्रपतिया की माति

⁴⁶ Presidium is the continuous government of the Soviet Union in fact as well as in law (p. 542). The virtual power of law making in thus in the hands of the Presidium. Further it interprets the law It has the power of removing and appointing officials including the Council of Ministers between sessions of the Soviet the shaping of the Cabinet and its entire control therefore lies with the Presidium.'—Finer op cit pp 666 67

The Presidium is the inter-personal web of Party and State" Finer Governments of Greater European Powers, p 680

उसके कोई विदोष अधिकार नहीं है। उसके अधिकारा का आधार उसकी राष्ट्रपति को स्थिति है जो सामूहिक सस्था के रूप म विश्लेष सत्तागुक्त होता है। ⁸⁸

पूजीवादी देशा म रूस की प्रेसीिडयम की माित राज्य शक्ति का प्रयोग करने वासा शासन का कोई अम नहीं होता है। इन देशों म राज्याच्यहा एक व्यक्ति—राजा या राष्ट्रपति—होता है। वह ससद के प्रति उत्तरवायी नहीं होता। वह ससद से उत्तर होता है। उसे ससद हारा पािरत विधिया पर निपेधाधिकार एव ससद के वियदन सम्बधी अधिकार प्राप्त होते हैं। सोवियत रूस में राज्याच्यक्ष एक व्यक्ति नहीं अपितु सुप्रोम सोवियत की एक सिनित होती है। स्टासिन इसे रूस मां (सामूहिक राष्ट्रपति कहता था।

लेकिन खुलियन डाउस्टर के अनुसार, प्रेसीडियम सोवियत राज्य का सामृहिक राष्ट्रपति नहीं है।' सत्य तो यह है कि प्रेसीडियम न सीवियत शामनतान के विवासी अस के रूप म अधिक नाय किया है। इसके काय अनेक प्रकार के है। ' एल जी खखबुड के अनुसार, 'प्रेसीडियम की व्यारया हम यह कह कर अच्छी प्रकार कर सकत ह कि वह खबस्थापिका एव सामृहिक राष्ट्रपति पद का समायय है। ' सत्य तो यह है कि प्रेसीडियम रूस की सर्वाच्च व्यवस्थापिका का सर्वाच्च रूप है। जो राष्ट्रपति एव मिन्मान्य के महत्व के सम्बाद के का या नो सम्पादित करता है। आग एव जिक्क ने प्रेसीडियम के महत्व के सम्बाद में कहा है कि उपलब्ध प्रमाणा से यह स्पष्ट होता है कि प्रेसीडियम के महत्व के सम्बाद में अहा है कि उपलब्ध प्रमाणा से यह स्पष्ट होता है कि प्रेसीडियम के शासन काथ के सम्यादन म अपने ज मदाता सुप्रीम सीवियत स कही अधिक सम्याद में अपने ज मदाता सुप्रीम सीवियत स कही अधिक सम्याद में अपने ज मदाता सुप्रीम सीवियत स कही अधिक समित में विचार विमाग एव निष्य कर लिय जाते हैं। अत वैद्याक सामलो, राष्ट्रीय सुरक्षा एव आ तरिक नीतिया में सता का सही व्यव्य में प्रेसीडियम हारा प्रयोग जसम्मव है। ' सत्य ता यह है कि प्रेसीडियम ने सभी व्यावहारिक अर्थों म सप्रीम सीवयत का आच्छादित कर सिवा है। है रहस जिक के जन्तार, ' ' में सीडियम स्वर्धा, ' ' में सीडियम

^{48 &#}x27;The Presidium of the Supreme Soviet is a collegiate President He has no such special rights as characterize the individual presidents of burgeous states. His rights flow out of his position as president of a collegium institution of Specialist Authority 'A Y Vyshinsky The Law of the Soviet State Chap V, pp 329 336

⁴⁹ Julian Towster Political Power in the U S S R p 272

⁵⁰ The Presidium may be best described as a combination of the legislative and collective presidency '—Churchwood L G Contemporary Societ Consument 1964, p 133

⁵¹ Ogg & Zink Modern Foreign Governments p 861

570 जिल्लानिक शासनतात्र

विधानमण्डलीय एव प्रशासकीय दाना ही प्रकार का अभिकरण है। एक तरफ प्रेसी डियम आय देशों में मित्रमण्डल द्वारा मम्पादित किये जान वाले कार्मी को सम्मादित करती है तो दूसरी सरफ उसके द्वारा उच्च सदन या कायपालिका परिपद के दायिता का सम्पादन किया जाता है। 1⁷²

^{52 &#}x27;It may be seen that the Presidium in both a legislative body and an administrative agency. It combines some of the functions performed in other countries by a Cabinet with those closely associated with an Upper Chamber or Executive Council, —Harold Zink. Modern Governments, 1962, p. 605

कुछ ग्रन्य देशो की कार्यपालिकाएँ [EXECUTIVES OF SOME OTHER COUNTRIES]

जापान¹ को कायंपालिका

19थी सदी के प्रारम्भ म जापान मे साम ती ढग की राजनीतिक एव सामाजिक स्ववस्था थी। जापान का वर्तमान सम्राट 600 ईसा पूव विषम् द्वारा स्थापित राज बद्य से सीचे सम्बन्धित है एव उसका वश्यप्र है। 1892 ई म मिनामोटी वस का एक व्यक्ति वास्ति कि राजक वाक्ष्य से सोचाट से 'सोगुन (Shogun) की उपाधि प्राप्त की जिसका अर्थ था महान् जनरल। सभी साम त उसक प्रति मक्ति उसत वे । 'सोगुन सम्बन्ध से पर्पाप्त विवास के प्रति मक्ति उसत वे । 'सोगुन सम्राट से परामच किये विवास है देश पर सासन करता था। बाद म मही पद एक प्रकार की सस्था वन गया था। 17वी सदी के प्रारम्भ म तोकुगीया जाति के सदस्या न वतमान टाकियो को, जिसे उस समय यीदो (Yedo) कहा जाता था,

जापानी वडे परिश्रमी एव लगनशील होत हैं । उनकी 75% जनसस्या कृषि पर निनर है परन्तु प्रति व्यक्ति न पास औमत 2 5 एनड स अधिक नृषि नहीं है । जापान न अभूतपूव वानिक एव औद्यागिर उप्रति की है । द्वितोध विवह । जापान न अभूतपूव वानिक एव औद्यागिर उप्रति की है । द्वितोध विवह स विना के कार पर पहुँच चुकन न बाद नी आज जापान विदय न समद राष्ट्रा म पिना जाता है।

आपान 20थो सदी के प्रयम चालीस वर्षों म विश्व की एक बढ़ी धिक्त यन नया या। 1930 ई के पहचात इहिक शासका की निति साम्राज्यवादी वन गयी थी। 1931 ई म जापान ने महर्पिया पर आश्रमण किया था। बाद म चीन क माय उसका मुद्ध हिंद गया। 1939 ई म उसके साम्राज्य का क्षेत्रपन 2,60,000 वगमील था। हिंदीय विश्वयुद्ध म चूरी राष्ट्रा (यभगी एव इस्ती) क साथ मिल कर मिनराप्ट्रा के विश्व जापान न युद्ध भाषित कर दिला था। प्रारम्भ म उस बढ़ी सफलता प्राप्त इस्ती सम्मण दिला पूर्वी एशिया एव यमा आदि पर जापान का प्रमुख स्थापित हो गया। ग एन्स्तु वाद में जापान युद्ध म हार गया। समुक्त राज्य अमरिका ह्यारा अमरत १५८ ई म अच्च-यम के प्रयाप न उन 10 वगस्त, 1945 ई को आसमसमण वरने क लिए याध्य कर दिया था।

अपनो राजधानी बनाया । 1867 इ तन यही स्पिति बनी रही । सागुन तन्त्र हारा विद्यासा का बुद्ध सुविधार एव नियायन प्रतान की सभी थी । एकत उनका तीज विशेष प्रारम्भ हो तथा और 1888 ई म सामानतार हो समाप्त कर दिया गमा तथा सम्प्रण भूमि को साम तो क स्वामि न स सखाट क स्वामित्व स हस्तातरित कर विया गया । सभी जापानिया का त्रिधक हरिट म समानता प्राप्त हुई एव वर्गीय विरोदारिकारण का जन कर दिया गया नथा सामातो को ब्यायार करने की छूट दी गयी।

1882 इ. म च्याट न राजकुमार ईटो को जापान म अब्छे शासन हेतु परिचमी शासन को सम्याजा को समीक्षा का काम भार सौंपा था। उसके प्रतिबदन पर 1889 इ. के सिंद्यान का निर्माण हुजा। इस मीजी मदियान थी कहते हैं। यह सिंद्यान प्रशा (Prussia) व सिंद्यान पर जापारित था एव 1945 ई. में जापान के पराजित होते तक चलना रहा। 1945 ई. में जापान के बतसान सिंद्यान का निर्माण हुजा था।

मोजी सविधान (1889 ई) के अन्तर्गत कायपालिका

कायपानिका व अतगन तीन सस्याएँ थी—सम्राट, सन्तिववक्त एव प्रीवी काउसल। जापान का सम्राट राज्य का अध्यक्ष था। उत्तम सम्मुता के व तमी अधि कार कि इत थे जिनका वह मविधान के अनुसार प्रयोग करता था। सविधान के अनुसार प्रयोग करता था। सविधान के अनुसार एक सिन-परिपद भी थी। इनका अध्यक्ष—प्रयानसन्ति कराम हाट के द्वारा जापान क वरिष्ठ राजनीतिना जि ह जिनरी (Gento) कहते थे, के परामस पर खुना जाना था। प्रधानम जी अपन महयोगिया को चुनता था। पित्र मक कि जुगानी ससन उद्दर्श हो। जाता को प्रधानम के याजनीतिक जीवन पर सैनिक वग वा प्रधान या वस्ति के जिनन पर सीनिक वग वा प्रधान से सीनिक जीवन पर सीनिक वग वा प्रधान स्थानि सीनिक वा सीनिक वीनिक जीवन पर सीनिक तर साम प्रधान से सीनिक वीनिक जीवन पर सीनिक वा वा प्रधान से सीनिक वीनिक जीवन पर सीनिक वा वा प्रधान सीनिक वीनिक जीवन वा वा प्रधान सीनिक वीनिक जीवन वा वा प्रधान सीनिक वीनिक वीनिक

जापानी सम्राट की क्विति मिविधान के अनुसार निरकुश शासक की थी। वह निरिद्ध सम्राट की माति सवधानिक अध्यक्ष मान नहीं था और न विधि के अपीन ही था। उसे अपदस्य नहीं विधा था सक्ता था। उसे ससद की नियनित करने पी शिक्त प्राप्त था। अप अध्यक्ष मान नहीं था और न विधि के अपीन ही था। उसे अपदस्य नहीं विधा था सक्ता था। उसे ससद की नियनित करने पी शिक्त प्राप्त था। अप अध्यक्ष था, युद्ध एव शानित तथा सिध्या करने एव समादान सम्ब धी व्यापक सिक्ता उसे प्राप्त थी। वह मित्रसण्यत के परामशी नुसार काम नहीं बरना था, कंत्र साम के विभागाध्यक्षी में ही परामण करता था। जिस प्रकार सरीर मित्रफल के नियम्ब प्रम होता है उसी प्रकार जापानी सम्राट का आइटो क अनुसार जापानी शासनत न पर नियम था। पर जु कुछ विधारक इससे मित्र मत रावते है। किरसावा के अनुसार वह सवधानिक अध्यम था, यविष उसने अनुसार जापान ने सम्राट म शासन की निवक शक्ति जिटिस राजा से कही

अधिक हं। सम्राट राज्य का अध्यक्ष थान कि शासन का। शासन के अधिकार मिन-मण्डल को प्राप्त थे।

यनागा (Yanaga) के अनुसार, 'यद्यपि सविधान द्वारा जापानी सम्राट को निरकुत धिक्तियो प्रदान की गयी है, परन्तु वह स्वय उनका प्रयोग नही करता। उसने सदैद ही मिन्रया के परामदा स काय किया है। जापानी यम्राट ब्रिटिश सम्राट से भी अधिक राज्य करता है न कि खासन।'

सम्बाद को सक्षेप म पाच प्रकार को शक्तिया प्राप्त थी (1) अपने परिवार सम्ब धी, (2) स्थल व नोसेना के अध्यक्ष के रूप में, (3) उपाधि वितरण सम्ब धी, (4) धामिक एव समारोहात्मक, एव (5) शासन सम्ब धी। वह स्वय जापानी ससद—बाहट—का सन आहूत करता था, तथा उसका उदधाटन करता था। उसे प्रतिनिधि सदन का विषटित करने का अधिकार था। वह विधेयको का त्वीकृति प्रदान करता था एव अध्यादेश जारी करता था तथा अधिकारियों को नियुक्त एव उनका वेतन निश्चित करता था। वह याथ का अन्तिम स्रोत था। सभी यायालय सम्राट के नाम पर याधिक काय करते था।

सामाजिक जीवन में उसका वडा प्रमाव था एवं समाज में उसका महत्वपूण स्थान था। जापानी विद्यार्थियों को स्कूलों में उसके प्रति निष्टा एवं मक्ति की शिक्षा दी जाती थीं तथा प्रत्यक शिक्षा संस्था में उसका चित्र टंगा रहता था।

प्रीवी काउसल

इसम एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एव 24 सदस्य होते ये जिह्न सम्राट प्रधान माधी के परामच से निमुक्त करता था। सम्राट द्वारा परामदा मागन पर यह परिषद उसे परामच सेता थी। इस सविद्यान की ध्यवस्था करते तथा सि न्या एव कुछ साम्रान्य वाध्या र विचार करते का अधिवार प्राप्त था। मि न्याप्टक के सदस्य प्रीची काउ सल से सदस्य प्रीची काउ सल से सदस्य हाते थे। लेकिन प्रीची पायद के रूप म व सम्राट का परामचा नहीं देत थे। प्रीची काउ सल जापानी डाइट क प्रति उत्तरदायी नहीं होती थी। मोशी सविधान के अत्यत्व प्रधानमं के ड्वा की ससदीय द्वासत व्यवस्था की स्थापना की गयी थी जिसके अत्यत्व प्रधानमं नी अपाट के प्रति उत्तरदायी होता था। जापानी मित्रमण्डल की यदि विदिश्व मिन्यम्ब्यत से तुलना की जाये तो दोनों मे अनेक अतर स्पप्ट हैं। यथा—जापान म प्रधानमं त्रीके लिए बहुमत दल का नेता होना आवस्यक नहीं था और न निम्न सदन — प्रतिनिधि सदन — म विषरीत मत आन पर प्रधानमं त्री की रामण्डल के विषरीय के कारण अनेक मिन्यों एव मिन्यस्था होन परदायाम करना पड़ा था। जापानी राजनीतिक जीवन म 'स्थोंच्य युद्ध सिति' (Supreme Wat

² C Yanaga Japanese People and Politics, p 137

Council) पर बडा प्रसाव था। सना एव नीसना के अध्यक्ष इसके सदस्य होते थे। मित्रमण्डल म त्रमण एव एक स्थान सवारत जनरल एव एडिमरन को प्रदान किया जाता था। इसम जावानी मित्रमण्डल म सना को अमीयित विदोषाधिकार प्राप्त हो यथे थे। मर्वाच्च युढ सिमित द्वारा यदि इन दो सदस्या को पदस्याग के आददा दै दियं जात थं तो उसके फरास्वए सम्भूण मित्रमण्डल को पदस्याग करना पढ़ता था। अवापानी सेना म पारस्परिक सहस्याग की विलिध्द मावना विद्यमान थी। सैनिक विधि कार्य होता में नी पत्र तभी प्रहण किया जाना था जबकि उसके बहुसस्यक सिनक सह योगी उसका समयन वरत ।। मर्वाच्च युढ सीमित की विदेशमात्री से परामय किया विता ही मन्नाट र नाम पर सना का युढ ह्यु तैयार होने या आक्षमण का आदश देन के अधिकार प्राप्त था। सना का जायानी कार्यन्त वरपूण नियावण था।

जापान का नवीन सविधान

हिनीय विश्वयुद्ध के उपरान्त जापान के आत्मसमपण के पश्चात अमेरिका सनाध्यक्ष जनरल मकायर हान जापानिया का अपने देश के लिए उदार एव लोकत नाम मिद्धा ता क अनुरूप नवीन मविधान वनान की प्रत्या प्रवान की गयी थी जिसके फल-करूप जापान का नवीन मविधान 1946 है से वनकर तथार हुआ और 3 मई, 1946 है से उस किमान सविधान में अपने के प्रत्या की गयी के प्रत्या की सर्वा के प्रत्या की सर्वा के अपने किमान सर्विधान में अमेरिका की अध्यक्ष मान के प्रत्या की अध्यक्ष मान के अध्यक्ष मान की अध्यक्ष मान की अध्यक्ष मान की अध्यक्ष मान की सर्वाय प्रणाली का उस पर विद्या प्रमाव है। आपपानिका शक्ति मिनप्रत्या मिहित है। जापानी सम्राट सर्वधानिक अध्यक्ष मान है। राजतन के देवी अधिकार का उ मुलन करके जन प्रमुख की स्थापाना की गनी है। जापानी ससद (बाइट) राज्य का सर्वोच्च प्रात्म की स्थापना की गनी है। जापानी ससद (बाइट) राज्य का सर्वोच्च प्रात्म की स्थापना की गनी है। जापानी ससद (बाइट) राज्य का सर्वोच्च प्रात्म की स्थापना की गनी है। जापानी ससद (बाइट) राज्य का सर्वोच्च प्रात्म की स्थापना की गनी है। जापानी ससद (बाइट) राज्य का सर्वोच्च प्राप्त की स्थापना की गनी है। जापानी ससद (बाइट) राज्य का सर्वोच्च प्राप्त स्थापना की गनी है। जापानी ससद (बाइट) राज्य का सर्वोच्च प्राप्त स्थापना की गनी है। जापानी ससद (बाइट) राज्य का सर्वोच्च प्राप्त स्थापना की गनी है। जापानी ससद (बाइट) राज्य का सर्वोच्च स्थापना स्थापना की गनी है। जापानी ससद (बाइट) राज्य का सर्वोच्च स्थापना की गनी है। जापानी ससद (बाइट) राज्य का सर्वोच्च स्थापना की गनी है। जापानी ससद (बाइट) राज्य का स्थापना की गनी है। जापानी ससद (बाइट) राज्य का स्थापना की गनी है। जापानी ससद (बाइट) राज्य का स्थापना की स्थापना की स्थापना का स्थापना की स्थापना का स्थापना का स्थापना की स्थापना स्थापना स्थापना की स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना

सम्राट

मझाट राज्य का प्रतीक है। उसकी शक्ति का स्रोत जनता है जिसम सम्प्रमृता निवास करती है। सम्राट का पद बशानुगत है एव उत्तराधिकार का निर्धारण जापानी ससदीय विधि द्वारा किये जाने की व्यवस्था की गयी है। मिनपान मे व्यवस्था है कि समार मिनमण्डल के परमार्थानुगार काय करेगा एव सिनमण्डल के सदस्य उसके कार्यों के लिए उत्तरदामी होगा कि राज्य सम्बन्धों केसल उही कार्यों को साह्य द्वारा सम्पादित किया जायेगा जिनकी सिन्धान ने व्यवस्था की है। शासन के सम्बन्ध में उसको कोई "कि प्राप्त नहीं है। "सम्राट को मिन्नमण्डल के परमदा एव स्थीकृति से जनता के नाम पर निम्न काय करने का अधिकार है सविधान, विधियाँ,

³ अनुच्छद 1

⁴ अनुच्छे> 3

अमुच्छेद 4

मित्रमण्डलीय आदेशी एव सिध्या के स्वाधन की घोषणा, डाइट को आहूल करना, प्रतिनिधि सदन का विघटन, सामा य निर्वाचन की घोषणा, राज्य मित्रयों की निष्रुक्ति एव पदच्युति तथा राजदूती एव मित्रयों के अधिकारा तथा उनके परिचय-पत्रा का प्रमाणीकरण, सामा य एव विशेष समादान, दण्ड को कम और स्थित करना तथा अधिकारों को पुन पदान करने पर प्रमाणित करना, सम्मान प्रदान करना, पुष्टीकरण एव अय राजनयक अलेखा को प्रमाणित करना, राजदूती एव अय मित्रयों वा स्वागत करना एव अवेक शिष्टाचार सम्बागी कार्या एवं अवेक शिष्टाचार सम्बची कार्यों की सम्यादित करना।

उपरोक्त विवरण सं यह स्पष्ट है कि सम्राट का पद औपचारिक है। उसकी क्यित भारत के राष्ट्रपति या ब्रिटिश समाट जैसी है। वह सबैधानिक अध्यक्ष मान है। मीजी सविधान के अत्तगत राजा का पद दवी था। वह ईश्वर की प्रतिमृति माना जाता था। इस मध्ययंगीन धारणा का अब अत हो गया है। आज वह सम्पण राज-नीतिक या नितक अधिकारा का स्रोत नहीं है। नवीन सविधान के अतगत वह शासन-तात्र म प्रतीक सात रह गया है। ब्रिटिश सम्राट की माति वह प्रधानमात्री की नियुक्ति नहीं करता अपितु जापानी सम्राट ढाइट द्वारा नियुक्त प्रधानमानी को औपचारिक रूप में नियुक्त करके एक रस्म अदा करता है। राजवश्च से सम्बधित मामला एव वित्त पर जापानी डाइट का नियानण है। जापानी सम्राट नाममान का अध्यक्ष है। परत बार्ड का मत है कि यह निष्कप गलत होगा कि जापान की राजनीतिक पदिति म उसकी मूमिका महत्वपूण नहीं है। किसी भी राष्ट्र को राष्ट्रीय एकता हेत प्रमावा-त्पादक राष्ट्रीय मावना प्रदान करने वाले प्रतीका की आवश्यकता होती है। जापान का राज-परिवार ऐसा ही प्रतीक है। वह दो हजार वप पूरानी जापानी राष्ट्रीयता एव सास्कृतिक एकता का प्रतीक है। वापान के सम्बाद वी शासन सम्बाधी शक्तिया के लुप्त हो जाने पर शाज भी जापान के सामाजिक जीवन म उसका मान-सम्मान कायम है। युद्ध के पश्चात सम्राट न जनता के मध्य घुमना प्रारम्भ कर दिया है। मीजी सविधान के अन्तगत राजनीतिक निणय सम्राट द्वारा स्वय नहीं किय जात थे। जत व्यवहार म उमकी स्थिति में बोई विशेष जातर नहीं हुआ है। एक महत्वपुण अतर यह अवस्य पडा है कि अब मात्री उसके नाम पर शासन नहीं करत है। उत्तर दायित्व की रेखाएँ पहले की अपेक्षा अब अधिक स्पष्ट हो गयी हैं। म जमक्रस

नवीन जापानी सविधान के अतगत कायपालिका द्यक्ति में त्रमण्डल में निहित है। सविधान के अनुसार मिनमण्डल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है एवं उत्तम अतिरिक्त अयं मंत्री होते हैं। यह ध्यवस्था की गयी है कि सित्रमण्डन में सुनी सदस्य

⁶ अनुच्छेद 7

⁷ Macridis and Ward Wodern Political System-Asia, p 91

जापानी नागरिक होंगं। नायपालिका शक्ति क प्रयाग के लिए मित्रमण्डल सामूहिक रूप से डाइट वं त्रीन उत्तरनायी हैं। स्पट्ट है जापान म मित्रमण्डलीय ध्यवस्या की स्थापना की गयी है।

जापानी गइट क सदस्यमण अपन म स निसी एक सदस्य की प्रस्तान पारित करक प्रधानम नी मनोनीन करत है। नवीन ससद व अधिवेदान के प्रारम्म होने पर सवप्रथम यह काय सम्पन निया जाता है। यदि बाइट के प्रतिनिधि सदन एव पापद सन्त अथात नाना सन्ता म इस प्रश्न पर कोई सबभेद उत्पन हो जाता है तो दोना सदना का संयुक्त अधिनखन जान्त किया जाता है और यदि दौना सदन फिर भी किसी निणय पर मही पहुचन या पापद सदन विद्यास काल को छोडकर कोई नवीन मास प्रस्तावित करन म असफल रहता है तो प्रतिनिधि सदन के निषम को डाइट का ही निणय माना जाता है। प्रधानम त्री हारा अय म त्रीमण नियुक्त किये जात हैं। वह मित्या का पल्ड्युत भी कर मकता है। अनुस्देद 68 के अनुसार अधिकास निर्वा चित मिनया का टाइट का सदस्य होमा चाहिए लेकिन व्यवहारत मिनमण्डल के ममी सन्त्य डाइट व सदस्या म स हो चुन जाते हैं। सविधान क द्वारा भिनमण्डल की सदस्य साया निर्धारित नहीं की गयी है। अनेक वर्षों से प्रधानमानी सहित मनि भण्डल क सदस्या की सच्या 17 रही है। प्रधानम नी का पर रिक्त होन या नव-निर्वाचन क्ष प्रचात डाइट का सम्मलन बुनाने पर सम्मूच मनिमण्डल की परत्याग करना पहता है। यदि प्रतिनिधि मदन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है या विश्वास प्रस्ताव का अस्वीकार कर दिया जाता है और प्रतिनिधि सदन प्रस्ताव पारित होन क हस दिन क भीतर निघटित नहीं होता तो सम्पूण मिनमण्डल पदस्याग कर देना है। उपरोक्त दोना न्यितियो म पुराना मन्त्रिमण्डल नदीन प्रधानमनी के चयन तक काम करना रहता है। मित्रयों के बिरुद्ध उनके कामकास म प्रधानमधी की अनुमति व बिना कोई विधिक कायबाही नहीं की जा सकती । मिनसण्डत के समी निषय सबसम्मति स किये जाते हैं। यदि काइ म त्री असहयत होता है तो उसके समक्ष त्यागपन के अतिरिक्त कोई के य विकल्प नहीं है।

मिनमण्डल के काय-प्रशासन सम्बन्धी सामाय काम मिनमण्डल करता है। कायपालिका सम्बंधी सभी महत्वपूष निषय मि नमण्डल हारा ही लिय जात हैं। भितमण्डल ही शासन की गीति निर्धारित नरता है एव विधियों को निष्ठाप्तक कियाचित करता है। इसक अतिरिक्त राज्यकाय का सवालन वदेशिक सम्बन्ध का निर्धारण सिंपयों करना देश का बाय यम सन्य धी विनरण तथा पर उस हाइट के समक्ष स्वीकृति हेंतु प्रस्तुत करता लाकतेया प्रशासन के नियमा एव मानका को निर्मारित करना सविधान एव राष्ट्रीय विधियों के किया चयन सम्बची जादेश देना, सामाय एवं विशेष क्षमा प्रदान करना मिनिमण्डल के अय दामिल हैं।

इसक अतिरिक्त मा त्रमण्डल ही अधिकास नियंपका के डाइट म स्वीकृति हेतु

एव विचाराथ प्रस्तुत वरती है। मात्रीगण उन्हं पारित करान के लिए भी उत्तरदायी

होते है ।

प्रधानमात्री मा त्रमण्डलीय पिरामिड के शीथ पर स्थित है। वह मा त्रमण्डल का अध्यक्ष है एव उसकी बठका वी अध्यक्षता करता है। उसकी स्थिति मात्रियों के जीवन मरण एव जाम की दिन्द से के द्वीय है। उसका त्यामपत्र सम्पूण मात्रमण्डल का त्यामपत्र साना जाता है। बाइट के समझ वह विषेयको एव विश्व न राष्ट्रीय व बंदे शिक मामलो पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, विश्व न प्रशासिक विभागा के कार्यों का निरीक्षण एव नियानण करता है, विश्व मात्रमण्डलीय आदेशों पर मात्रमण्डलीय साम्रणस्त्र करता है, विश्व मात्रमण्डल करता है, विश्व मात्रमण्डल करता है, विश्व मात्रमण्डल करता है।

प्रधानमानी के यह के लिए निम्न विधिक योग्यताला का होना अनिवाय है (1) यह असिक लायानी नागरिक होना चाहिए, (2) उस जायानी हाइट का सदस्य होना चाहिए एव (3) उसे निम्म सदन व प्रतिनिधि सदन का बहुमत प्राप्त होना चाहिए। यदि निम्म सदन म किसी दल को स्पप्त दक्षमत प्राप्त होना चाहिए। यदि निम्म सदन म किसी दल को स्पप्त दक्षमत प्राप्त होते प्रधानमानी को उसका नेता होना चाहिए या अय दला का सहयोग प्राप्त करके उसे अपना बहुमत स्थापित करना चाहिए। अत देश का कोई प्रमुख नेता जिसे राजनीतिक मूम्बून्द प्रधासिन कथाना, लोकप्रियता, दलीय विश्वास आदि प्रजुर माना म प्राप्त हो, रुवानमानी पर का स्थण देख सकता है। अपने दल म उसकी स्थित का नीय हान्य हा सासन का वह प्रमुख प्रक्ता होता है। वह कायपालिका का प्रमुख है। उनका न्याप्त का वह प्रमुख प्रवक्ता होता है। वह कायपालिका का प्रमुख है। उनका न्याप्त का वह प्रमुख प्रवक्ता होता है। वह देश को सर्वोक्त राजनीतिक नेक्टून रूपन करता है।

तथीन जापानी सविधान द्वारा ससवीय कायपालिका की न्यास्त को गरी है। प्रधानमात्री का अपना सचिवालय होता है। प्रधानमत्री के अमार्क्त निवान-स्थान पर मित्रमण्डल की बठके होती हैं। प्रधानमात्री की उनुम्निक्त में दर प्रधानमात्री अध्यक्षता करता है। मित्रमण्डल की बठकें पुत्त हार्ज हैं "व कोई मजूरि समुद्धि अध्यक्षता करता है। मित्रमण्डल की बठकें पुत्त हार्ज हैं "व कोई मजूरि समुद्धि तिया होती है। मित्रमण्डल में बत्र मित्रमण्डल की बठकें पुत्त हरें मित्रमण्डलीय सिन्मिक्त को मित्रमण्डलीय सिन्मिक्त हो। मित्रमण्डलीय सिन्मित्या ही पढ़ ही प्रमुख मित्रमण्डलीय सिन्मित्या है।

साम्यवादी चीन की कार्यपानिका

1949 ई. में सारे बीन पर साम्बबादियों का अधिक न स्वापित है. क्या र्ज सितान्वर 1949 ई. में साम्यबादी दल ने चीन में उत्तवादी उन्तवता की स्थापन

⁸ चीन एक विशाल जनसस्या एव शैक्टक कान्य देश है ।

घोषणा की थी। 1950 इ. म. चीनी जनवादी सरकार म अधिनादा तटवर्ती द्वीपा पर भी अधिकार कर लिया। सितम्बर 1949 इ. म. सितम्बर 1954 ई. तक दासन चीन के जनवादी गणत न की जनता के के द्वीय झासन के सावयंथी निवम (Organic Law) के अनुसार होता रहा। इस नाल म. चीन किसानो एव अधिकार समा सोने लोकता निक अनुसार होता रहा। इस नाल म. चीन किसानो एव अधिकार समा सोने लोकता निक को प्राप्त का ताला को नाणि के द्वीयकरण के विद्वान पर आधारित था। नवीन सिवधान का निर्माण के द्वीय जनवादी शासन द्वारा निवुक्त एक समिति ने विषया था और सम्यूण देश म उस पर विचार हुआ था। सितम्बर 1954 ई. म. राष्ट्रीय जन की येस द्वारा इसका कुछ सद्याधना सहित स्वीकार किया गया। चीनी जनवादी गयात व की कायपालिका शक्ति चीनी गण राज्य के अध्यक्ष म निहित है। इसके अतिरिक्त राज्य परिषद (State Council) नामक एक अप सस्था भी है जो सविधान क अनुतार के द्वीय सातन है एव राज्यसत्ता का सवींच्य ना सवींच्या नायपालक तथा सवींच्या प्राराविक करा है। पर राज्यसत्ता का सवींच्या ना सवींच्या का सवींच्या ना सवींच्या ना सवींच्या ना सवींच्या ना सवींच्या नायपालक तथा सवींच्या ना सवींच्या करा है। पर राज्यसत्ता का सवींच्या ना सवींच्या ना सवींच्या नायपालक तथा सवींच्या ना सवींच्या करा है। इस सविधान क अनुतार के द्वीय सातन है एव राज्यसत्ता का सवींच्या ना सवींच्या ना सवींच्या ना सवींच्या नायपालक तथा सवींच्या पर सवींच्या करा है।

गणराज्य का अध्यक्ष

गणराज्य के अध्यक्ष को राष्ट्रीय जन बांग्रेस द्वारा बार वय के लिए चुना जाता है। प्रत्यक चीनी नागरिक जो राजनीतिक अधिकारा का उपमीप करता है तथा 35 वप की अवस्था प्राप्त कर चुकता है, गणराज्य के अध्यक्ष पर पर निर्वाचित हो सकता है। एक उपाध्यक्ष भी होता है जो अध्यक्ष को उसके कार्यों म सहयोग देता है एव वह ऐसे सभी कार्यों को सम्प्रादित करता है जो अध्यक्ष द्वारा उसे सांचे जाते हैं। उपाध्यक्ष पर के लिए वही योग्यनाएँ हैं जो अध्यक्ष पर के लिए हीं। अध्यक्ष की अनुप्रदिचित म या दीपकाल तक उसके अस्वस्थ रहने पर उपाध्यक्ष उसके स्थान पर कार्यक्ष का अपकाल के स्थान पर कार्यक का स्थान पर कार्यक कार्यक का स्थान पर कार्यक कार्यक हों।

काय एव शांक्या—चीनी जनवादी गणराज्य के अव्यक्ष को ब्यापक शांकिया प्राप्त है। यह राष्ट्रीय जनवादी गांग्रेस या उसकी स्थायी समिति के निगयों को किया वित करता है, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मित्रयों, समितियों के अव्यक्षी एवं मी निग्रक एवं परच्युत करती है, उपाया पर्याप्त करता है, सामा य समादात एवं समा के अयोदी, परक एवं सस्मान अञ्चल करता है, सामा य समादात एवं समा के आदेशों, माशल ला एवं युद्धानस्था की पोपणा करता है तथा सामाय सनिक महीं वे आदेश देता है। 10 विदेशी राज्यों के साथ चीन के सम्बच्धों में वह अपने देश का प्रतिनिधियं वरता है, विदेशी राज्युती का स्वागत एवं विदेशों मं चीनी

10 अनुच्छेद 40

⁹ The organic law of the central people's government of the People's Republic of China

राजदूता को निगुक्त करता है, सर्वाधिकारी राजदूता को वापस बुलाता है एव विदेशों म की गयी सिष्मां की पुष्टि करता है । 13 चीन की सनिक कमान उसके हाया म होती है एव वह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होता है । 2 वह राज्य के सर्वोच्च सम्मेतन ना स्वच्छा से आहुत करता है एव उसकी अध्यक्षता करता है। (अनुच्छेद 43)

राज्य परिषद

राज्य परिषद चीन का के द्रीय शासन है। यह कायपालिका का सर्वोच्च प्रशास-निक जग है। 18 सामा य मापा म यही चीन का मन्मिण्डल है। इसका सगठन विधि द्वारा निर्धारित है। 18 प्रधानमन्त्री, उप-प्रधानमन्त्री, मन्त्री, आयोधा के अध्यक्ष एव

¹¹ अनुच्छेद 41

¹² जनुष्देद 42

¹³ सर्वोच्च राज्य सम्मेलन (Supreme State Conference) की बठक चीन के अध्यक्ष द्वारा है। चुलायी जाती है। वह इसकी अध्यक्षता करात है। इसके जिल-रिक्त गणतान ना अध्यक्ष, जनकायेस की स्थायी स्पिति का समापति, प्रधान-मनी, राज्य परिपद का समापति, तथा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत दो अय व्यक्ति इस सम्मेलन के सदस्य होते है। इसमें राष्ट्र के महत्यपुण मामलो पर पिचार किया जाता है। यह विचार अध्यक्षक का सावजिक स्थान है। इसमें अध्यक्ष को स्थाय के स्थाय के स्थाय के स्थाय की स्थाय करता के समक्ष रखने का अध्यक्ष होता है।

¹⁴ यह चीन के सर्वोच्च सिनक अधिकारियों का निकास है। इसमें गणतात्र कं अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अतिरिक्त 15 उपाध्यक्ष एवं 81 साधारण सदस्य होते हैं।

¹⁵ अनुच्छेद 47

¹⁶ जनच्छेद 48

580 | आधुनिक शासनत व

सिववालय के प्रधान इसने सदस्य होन हैं। प्रधानमन्त्री राज्य परिषद का सवालत करता है एव उसके अधिवसना की अध्यक्षता करता है। उप प्रधानम त्री प्रधानम त्री कं कार्यों म सहयोग प्रदान करता है। "म त्री एव आगोगा के अध्यक्षा का काय अपने दिसामा की देखमाल करना है। अपने विभागीय क्षेत्रा म ने राज्य परिषद के निणया, आदेशों एव विधिया के अनुस्य आदेशों कर सकते हैं। "राज्य परिषद राष्ट्रीय जनकांग्रिस च प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है और उसक समक्ष अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत बरती है। "राष्ट्रीय जनकांग्रिस के सदस्या को परिषद या उसके सत्रावसात कात्र म उसकी स्थायी सीमित से प्रस्त पूछने का अधिकार प्राप्त है।

परिपव क काय एव शक्तियाँ—सद्येष म, राज्य परिपद क काय एव शक्तियाँ तिम्नवन हैं °

- प्रशासकीय मामलो को निर्धारित करना, आदेश एव आकाएँ जारी करना तथा उनने किया वयन का निरीक्षण करना ।
- (2) राष्ट्रीय जनकांग्रेस या उसकी स्थायी समिति के समक्ष विधेयको को प्रस्तुत करना ।
- (3) विभिन्न विभागो ने नायों में समज्ञय करता एवं उनका मागदशन करता।
 (4) विभिन्न मिनियो या आयोगा एवं राज्य के स्थानीय दासन क अंगे के
- अनुचित आदेशां को संघोधित या समाप्त घोषित करना।
 (5) राष्ट्रीय नायिक योजना और बजट को किपान्वित करना।
 - (6) विदेशी एव भातिरक व्यापार का नियमित करना। (7) सास्कृतिक शक्षणिक एव स्वास्थ्य सम्बाधी कार्यों का सवालन।
 - (8) विभिन्न राष्ट्रीयताओं सम्बंधी कार्यों का सचार (8)
 - (9) प्रवासी चीनिया एव तत्सम्बन्धी मामला का प्रशासन ।
 (10) राज्य हित एव सावजनिक शांति तथा नागरिक अधिकारों नी रसा ।
 - (11) विदसी मामलो का सचालन ।
 - (12) सशस्य शक्ति का निर्माण ।
 - (13) प्रशासकीय अधिकारिया का नियमानुसार नियुक्त एव पदच्युत करना ।
- (14) स्वशासित जिला, क्षेत्रा एव नगरपातिकाओ के पद तथा क्षत्रों को मायता दता।

¹⁷ अनुस्दद 50 18 अनुस्केंद्र 51

¹⁹ अनुच्छन 52

²⁰ अनुच्छ्रेन 49

(15) राष्ट्रीय कश्चिस या उसकी स्थायी सिमिति द्वारा सौंप गये अय कार्यों का सम्यादन ।

प्रति माह राज्य परिषद का एक सामान्य सम्मेलन होता है पर तु परिषद के अधिवधान सामान्यत होत ही रहत हैं। परिषद के अधिवधान की अध्यक्षता एव उसका काय-सचालन प्रधानम भी करता है। कायकारिणी की वठका में केवल प्रधानम भी, उप प्रधानम भी, मन्त्रीगण एव महासचिव ही माग लेत है। इसके विषयीत परिषद के मासिक सामान्य सम्मेलना म प्रधानमन्त्री एव उप प्रधानम भी के अतिरिक्त अन्य सभी मन्त्रीगण एव आयोगों के अध्यक्ष भी मागलेत हैं। राज्य परिषद का एक अपना सचिवालन होता है जिसका प्रमुख महासचिव होता है।

समोक्षा-राज्य परिषद को ब्यापक एव प्रमावी शक्तियाँ प्राप्त हैं । सम्पण प्रशासन उसके निर्देशन एव नियात्रण म चलता है। परिषद मित्रमण्डल जैसी एव सस्या है। परिषद का राष्ट्रीय समा के प्रति उत्तरदायित्व एवं परिषद से प्रश्न पछने क अधिकार स ऐसा लगता है कि साम्यवादी चीन में ससदीय प्रणाली की अपनाया गया है। पर तु यह केवल भ्रम है। इन व्यवस्थाओं के कारण चीन की शासन व्यवस्था की उत्तरदायी शासन नहीं कहा जा सकता । प्रधानमात्री शासन का अध्यक्ष नहीं है, न सामहिक उत्तरदायित्व के सिद्धात को ही मा यता दी गयी है । परिषद के सदस्य ससदीय सरकार की मांति एक टीम की तरह प्रधानमात्री का नेतल्व स्वीकार नहीं करते और न उसके प्रति उत्तरदायी ही होत है। परिषद के सदस्या के निर्वाचन म प्रधानम ती का कोई हाय नही होता । सभी सदस्य साम्यवादी दल के प्रभावदाली सदस्य होत हैं। अय ससदीय देशा की भांति प्रधानमात्री को विधानमण्डल को विध-दित करने के अधिकार प्राप्त नहीं हैं। सविधान के अनुसार मित्रयों के लिए प्रधानमात्री की सहायता करना अनिवास है। पर त सत्य यह है कि प्रधानम नी एवं जब सभी म ती तो साम्यवादी दल के शीयस्थ नेताओं के इशारे पर नाचते हैं। चीन का शासन लोकता त्रिक के दीकरण के सिद्धात पर गठित है। अ य साम्यवादी देशों की माति चीन म भी लोकत त की अपेक्षा दलीय ने दीकरण का प्रायल्य है। अत चीन में भी साम्य वादी दल का अधिनायकत न है। देश म साम्यवादी दल ही एकमात्र दल है। विराधी दल की कल्पना ही नही की जा सकती । सत्य तो यह है कि चीन म ससदीय शासन की छाया भात भी नही है।

चीन में दल एवं शासन में घनिष्ठ सम्ब घ है। सभी निषय दल की पोलिट-ब्यूरो द्वारा लिय जात हैं एवं शासन केवल उनको विधिक रूप प्रदान करता है।

कनाडा मे कार्यपालिका

कनाडा की सधीय कायपालिका भ तीन अग है—-काउन, यवनर जनरल एव मित्रमण्डल । इनको दो मागा मे वर्गीकृत कर सकते है (1) नाममात्र की काय- 🗸 पालिका, एव (2) वास्तविक कायपालिका । त्राउन एव गवनर जनरत कनाडा की नाममात्र की कायपालिका है, मित्रमण्डल वहा की वास्तविक कायपालिका है।

काउन एवं गवनर जनरल

कनाडा के सविधान—विटिश नाँव अमेरिका अधिनियम—के अनुप्तार कनाडा की वायकारियो शक्ति नाउन मे निहित है। ब्रिटिश राजा या रानी कनाडा के मो राजा या रानी होते है। ब्रिटिश राजा या रानी कनाडा को मो राजा नहीं है अधिन ब्रिटिश राजा या रानी को कनाडा का राजा नहीं है अधिन ब्रिटिश राजा या रानी को कनाडा का राजा या रानी याना राजा नहीं है अधिन ब्रिटिश राजा या रानी को कनाडा का राजा या रानी याना रायटमण्डल की सदस्यता को कनाडा द्वारा स्वेच्छा से स्वीकार करने का बोनक है। ब्रिटिश नाउन ग्रेट निटन को उसक उपनिवेशो से जोड़ने वाला स्विथम मुत्र है। कताडा को ससद द्वारा पाणित विधिया को ग्रवनर जनराव के समक्ष रानी की हित्त किया जाना था। जिन विधेयकों को रानी के हस्ताक्षर के लिए रोक विया जाना था व नगी पारिन होते थे जबकि आगामी दो वर्षों की अवधि म ग्रवनर जनराव उद्दे अपने हन्ताक्षर युक्त स्वश सं प्रमाणित कर देताथा कि इन विधेयकों को मानी विधेयन सिद्धा त मे राजा महित समद ही ग्रारित करती है पर बु व्यवहार म राजा के निपेशा धिकार का दीधकाल से प्रयोग न होने के कारण वह निरस्त हा चुका है। बतमान म कनाडा की ससद हु प्रकार की विधि बनाने की धमता रखती है।

काउन के काय जिटिश राजा जैस है। कनाडा म काउन के इन कार्या को गवनर जनरल सम्यादिन करता है। वह (यननर जनरल) क्राउन का प्रतिनिधि होता है। कनाडा से सम्बीधन करता है। वह (यननर जनरल) क्राउन का प्रतिनिधि होता है। कार्या से कार्या सम्वीधनार सम्य राजदूता या मित्रया की नियुक्ति आदि—को क्राउन क्या हो ने लिन कपिकाश से काउन की शक्तियों का प्रयोग यननर जनरल हारा निया जाता है। पर तु इन बोना ही स्थिनियों म कनाडा की सरकार से परामय आवश्यक होता है। पहले यननर जनरल की नियुक्ति प्रदिख्य शामन हारा की जाती यी पर तु 1930 ई म मात्राजीय सम्येनन (Imperial Conference) के निश्चया मुसार गवनर जनरल को कनाडा के शायन की इच्छानुसार हो चुना जाता है। इस व्यवस्था के अनुमार लाई बेशवरा (Lord Bessbourgh) को 9 करवरी, 1931 ई को मनान की सरगार क उत्तरदायिल पर यननर जनरल नियुक्त किया पया था। स्मरणीय है कि आज यो यननर जनरर एव अय यदाधिकारी जिटिश सम्राट क प्रतिस्थानियनित की दापण लेन है।

गवनर जनरत वा कायकाल सामायत थांच वप है, यदापि ननाडा के साधन या गवनर जनरत वो पदच्युन करन अधवा वापस कुलान की मीम करने का अधिकार प्राप्त है। सामायत वह अपने पूरे कालपम त अधात् 5 वय तक पदास्त्र रहता है। सवर्गर जनरल की शक्तियाँ—काउन के प्रतिनिधि के रूप मे गवनर जनरल को ससद को आहूत एव स्थाित करने तथा विषटित करने में के अधिकार प्राप्त है। वह सीनेट के सदस्यों का चयन करता है एव रिक्त स्थानों की पूर्ति करता है। उसी की सिकारिश पर कॉम स समा में कर प्रस्ताय प्रस्तुत किये वाते है। वह कायपालिका का अध्यक्ष है। संयुक्त राब्द्र सथ में वह कायबालिका का अध्यक्ष है। संयुक्त राब्द्र सथ में वह कनावा के प्रतिनिधि की नियुक्ति करता है। उसे कनावा के प्रति कर सहस्य की सिध्या करने का अधिकार प्राप्त है। उसे कनावा के प्रा तो के उप-राज्यालों तथा सीनेट के अध्यक्ष (Speaker) को नियुक्त एव पदच्युत करते के अधिकार प्राप्त हैं। सर्वोच्च एव प्रा तीय यायालया के यायाधीशों को भी वह नियुक्त करता है एव सीनेट और प्रतिनिधि सदन के सम्बोधन पर उह पदच्युत कर सकता है। उसे प्रातीय विधिया को अस्वीकार करने तथा विधिया को राजन की स्वीकृति हेतु रोकने के अधिकार प्राप्त है। शांति-काल में बहु यल, नम एव नीसेना के उद्देश निर्यारित करता है। उसे क्षमादान एव दण्ड कम करने के अधिकार प्राप्त है। असे कमादान एव दण्ड कम करने के अधिकार प्राप्त है। उसे समादान एव दण्ड कम करने के अधिकार प्राप्त है। सावान प्राप्त है क्षम करने के अधिकार प्राप्त है। स्थाना प्राप्त है कि समादान एव दण्ड कम करने के अधिकार प्राप्त है। उसे क्षम करने के अधिकार प्राप्त है। उसे क्षम करने के अधिकार प्राप्त है। असे क्षम करने के क्षम करने के अधिकार प्राप्त है। असे क्षम करने के अधिकार प्राप्त है। असे क्षम करने के क्षम करने के अधिकार प्राप्त है। असे क्षम करने के क्षम करने के अधिकार प्राप्त है। असे क्षम करने के क्षम करने के अधिकार प्राप्त है। स्राप्त क्षम करने के क्षम करने के अधिकार प्राप्त है। स्राप्त क्षम करने के क्षम करने के अधिकार प्राप्त की स्था क्षम करने के क्षम करने के अधिकार प्राप्त है।

वह अनक सामाजिक कार्यों एव समारोहों में भाग लेता है। समय समय पर सयुक्त राज्य असेरिका के सार देश के कूटनीतिक सन्दाधा को सुधारने म उसका विशेष योगदान रहा है। उसके अनेक महत्वपूण कार्यां म सं एक महत्वपूण कार्य प्रधान-मानी का चयन करना है। अल्पसरयको हारा अपन अधिकारों की रक्षा के लिए गवनर जनरल से ही प्रायना की जाती है।

गवनर जनरल को सविधान की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने ना अधिकार मी प्राप्त है। प्रधानमानी द्वारा रिस्वत लेने अथवा पवन्याय से इक्लार करने या किसी समस्या पर विचार हेतु ससव को आहृत करने सम्ब धी पवनर जनरल के परामय को न मानने पर गवनर जनरल को प्रधानमानी को पवच्युत करने का अधिकार प्राप्त है। प्रधानमानी के आग्रह पर यदि वह ससद को एक बार विघटित कर देता है और नवनिर्वाचित ससद में भी प्रधानमानी अल्पमत में रहता है ता मिनमण्डल द्वारा ससद का पुन विघटित करने की प्रधानमा को गवनर जनरल अस्वीकार कर सकता है। सत्ते हो ऐसे अवसर कम हा, पर तु इस तथ्य की जानकारी कि गवनर जनरल को प्रधानमानी की इस प्रकार की प्रधानमा को अस्वीकार करने का अधिकार है, एसी स्थिति के उत्पाद होने के अवसर हो वही रहते। यवनर जनरल को प्रधानमानी की काली है और उन्हें हुत करने में यह अपन प्रमान का उपयोग करता है। चूकि गवनर जनरल को राजनीतिक घरिन प्रधान का स्थान है अत उत्पत्ती मध्यस्थता का स्थान र जनरल को राजनीतिक घरिन प्रधान मध्यस्थता का स्थान होती है अत उत्पत्ती स्थान सम्बस्थता का स्थान किया जाता है।

^{21 1926} ई के बाइन काण्ड (Bying episode) स यह अन्तिम रूप म तय हा चुका है कि विषटन को शिक्त प्रधानम श्री को प्राप्त है और गवनर जनरल इस सम्बाध म उसकी प्राथना को अस्तीकार नहीं कर सकता।

स्थिति—यद्यपि गवनर जनरत कायपालिका का अध्यक्ष होता है परंतु वह बपनी शक्तिया का ययोग मित्रमण्डल क परामच से ही करता है। मित्रमण्डल के संदरमो एव मित्रमण्डल क कार्यों म वह हस्तदीय नहीं करता। मित्रमण्डल ही उसक नाम पर कियं जाने वाले समस्त कार्यों के लिए उत्तरहायी होता है। मि निमण्डल क विचार विमस म वह माम नहीं नेता है। डमूक आफ अमस (Duke of Argyle) ने, जो 1878 ई से 1883 ई तक कनाड़ा क गवनर जनरल रहे थे, मित्रमण्डल के अधिवेदाना में माग तेना छोड़ दिया था। उसके परचात यह एक परामरा ही गयी हैं और अमल के सभी उत्तराधिकारिया द्वारा इसका अनुमान किया गया है। वह दलीय पक्षपात से हर रहता है। उसका इच्छिकोण विसुद निवलीय होता है। काम स समा म जिस दल का बहुमत होता है उसी के नता को वह प्रधानमं में एव उसी दल म से मिनमण्डल क सदस्यों को नियुक्त करता है। उसे समकासीन राजनीति या आयित समस्याओ पर विचार व्यक्त करने के बहुत कम अबसर प्राप्त होते हैं। 1926 ई के वस्त्रात गवनर जनरत को समस्त राजनिक दायितों सं पुषक कर दिया गया है और अब उन कार्यों को हाई कमिस्तर हारा सम्पादित किया जाता है।

गवनर जनरत बस्तुत सर्वधानिक अध्यक्ष है। उसकी दुलना ब्रिटिस राजा से की जाती है तथा उस उसके समकक्ष माना जाता है। विक्रिन दौना की स्थिति में पर्यास अंतर है। क्रांडा का मननर जनरत वहां की सरकार हारा मनीनीत होता है तथा उसका कायकाल निविचत होता है। उसका पर बिटिश राजा की माति वसानुगत नही हैं, फलस्वरूप वह बिटिश राजा की मीति राष्ट्रीय सम्मान का पान नहीं है और न वह जिटिस राजा को माति राज्य का अध्यक्ष ही है। बिटिस राजा बिटिस राज्य एव साम्राज्य का प्रतीक है। यह देशमिन का कद्र है। इसके विवरीत, बनाडा का गृह नर जनरत सर राबट बोडन के सब्दों में, मनोनीत राष्ट्रपति है जो बिटिस राजा की माति शायद ही मित्ता एवं जनमावनाओं को उद्वेतित कर सके। पवनर जनस्त को तिहिश राजा की माति शासन का वीयकालीन अनुमन नहीं होता। यननर जनरत के पद पर अपने म स ही किसी कनाडावासी की नियुक्ति को अनेक कनाडावासिया द्वारा स देह की हिट्ट से देखा जाता है और इसे वे एक अच्छी परस्परा नहीं मानते। इसक कारण गवनर जनरत की निवसीय स्थिति ने समाप्त होने की अधिक सम्मावना है। 1952 है में नियुक्त गवनर जनरल श्री विनसेट मसी प्रथम ननाडा वासी थ। उदार दल सं उनके दीयकालीन सम्बच रहे थ। वे एक वार उदारस्तीय मित्रिमण्डल क संदस्य भी रह चुके थे। इसे स्वस्थ परम्परा नहीं माना यया है एवं यह संदह व्यक्त किया जाने तथा है कि गवनर जनरत देश की दतीय राजनीति एव विकारों से अपने को पथक नहीं रख सक्या। प्रीवी काउ सल

.... सर्विधान द्वारा एक भीवी परियद शा निर्माण किया गया है। इसका काय

गवनर जनरल को देश कं प्रशासन काय में सहायता एव परामश्च देना है। इसकें सदस्यों को गवनर जनरल समय समय पर चुनकर मनोनीत करता है एव वे प्रीची पापदा के रूप में दायथ लेते हैं। गवनर जनरल ही इन्न पद्ध्युत कर सकता है। व जत प्रीची परिपद सहायता एव परामश्च देने वाला एकमान विधिव निकाय है। पर जु अवहार में सम्प्रण प्रीची परिपद परामश्च नेही देती, न पूरी परिपद कमी पद- मुक्त ही होती है। 1867 ई के परचात सम्प्रण प्रीची परिपद की दो अवसरों के अतिरिक्त कोई बठक नहीं हुई है। इसकी सदस्य सख्या 113 है और सदस्यता का काल जीवनप्य त होता है। मिनण्डल के सभी सदस्य परिपद के सदस्य हीते हैं। इसके अतिरिक्त नमें प्रातिष्ठित मानामानी के प्रतिप्त के समी प्रवानमानी, प्रतिपुत्र मानामानी, प्रतिपुत्र मानामान के सम्बन्ध स्वयं होते है। 1953 ई के परचात कनाडा के मुर्य यायाधीश, काम स समा एव सीनेट के अध्यक्ष तथा विरोधी दल के नेताओं को भी प्रीची पापद नियुत्तर किया जाने लगा है।

एक फायकारी निकाय के रूप भे प्रीवी परिपद की कभी कोई बैठक नही होती है। परिपद के सबधानिक दायित्वों को मी त्रमण्डल द्वारा सम्पादित किया जाता है। मित्रमण्डल एव प्रीवी परिपद के जातर को इस कथन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है कि हर मात्री प्रीवी पायद है परातु हर प्रीवी पायद मात्री नही होता है। दूसर सब्दा मे, मित्रमण्डल प्रीवी परिपद की एक उपसमिति होती है।

मि जिमण्डल

मिं तमण्डल कनाडा की थास्तविक एव राजनीतिक कायपालिका तथा राजनीतिक शक्ति का चालक चक्र है । यह नीति निर्माता एव सर्वोच्च निर्देशक शक्ति है तथा समस्त प्रशासनिक कार्यों को नियित्रत एव तिर्देशित करती है। कनाडा के मित्रमण्डल ना ब्रिटिश मित्रमण्डल की शांति कोई विधिक आधार नहीं है। यह एक अतिरिक्त संविश्वाल (Extra Constitutional) सस्या है, यह प्रीवी पिरव की एक समिति है। इतके कार्यों को प्रीवी परियद के नार्यों के रूप में चैयता प्रास्त है। कनाडा में सम्भूण मित्रमण्डलीय व्यवस्था असिसमय पर आयारित है।

नताडा मे मित्रमण्डल (Cabinet) एव मित्र परिषद (Ministry) का प्रयोग समाजार्थी दावदी क रूप म होता है पर तु दाना म अतर है। मित्रमण्डल एक समु वृत्त है जबकि मित्रमण्डल एक समु वृत्त है जबकि मित्रमण्डल के सहस्य नहीं होत है। मित्रमण्डलोभ सदस्य होत है। उनम से सभी मित्रमण्डल के सहस्य नहीं होत है। मित्रमण्डलोभ सदस्य अधिक महत्व होता है। इनको सदस्य महामा यत 20 हाती है। यित्रमरिषद म 27 से 31 तक सहस्य हात है। मित्रमण्डल म 14-15 विमानाप्यक्ष मन्त्री हात है। वे प्रधानमन्त्री के घनिष्ट सहयोगी होत हैं। वे प्रधानमन्त्री के विनाद विमाण क

²² Section II of the North British America Act

म त्री होत है। इसके अतिरिक्त ससदीय सहायक (Parhamentary Assistant) त्री होते हैं जो मिन्त्रिमण्डल के अधिवेशनों में माग नहीं लेते। नीति निणय से इनका कोई सम्बन्ध नहीं होता और न वे विभाग की अध्यक्षता ही करते हैं। यह इमलण्ड के उप मिन्या की माति होते हैं।

मिनमण्डल का गठम--गवनर जनरल नविनिर्वाचन या काम स समा म मिन करला है। सदन में यदि स्पष्ट बहुमत है वो प्रधानमंत्री के पद पर आम नित करला है। सदन में यदि स्पष्ट बहुमत है वो प्रधानमंत्री का चयन अत्य त तरले होता है, परमु स्पष्ट बहुमत के अमाव या व्हाय मतभेवी की स्थित म गवनर जनरल को प्रधानमंत्री के चुनाव में पर्याप्त स्वल तला प्राप्त हो जाती है। ऐसी स्थित म गवनर जनरल स्थायी एव इंड सरकार के निर्माण के लिए जिनसे चाहे प्रधान कर कर सकता है। प्रधानमंत्री सर जान चाँमधन के उत्तराधिकारी की खोज म गवनर जन रल लाँड एवरडीन ने 1897 ई मं यही किया था। वह अय वरीका भी अपना मकता है। वह सम्मानित नेताओ से विचार विमन्न करके प्रधानमंत्री का चुनाव कर सकता है। लाड एवरडीन ने सबप्रथम सर डोनाल्ड स्मिय से वार्तो की धी पर तु सर चाल्स स्प्पर की प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। उपरोक्त दो अवसरा के अतिरिक्त कनाडा से गवनर जनरल को प्रधानमंत्री के चयन मे स्विविक के प्रयोग का करी जनसर प्राप्त नही हुआ है। मिन्नाव्हल के सबस्यों के चयन में गवनर जनरल प्रधान मंत्री के परामण की अनिवायत स्वीकार करता है।

कनाडा का प्रधानमन्त्री अपने सहयोगिया के चुनाव म द्विटिंग प्रधानमात्री की माति स्वत न नहीं है । उसे अपने मा निमण्डल म सभी प्रमुख जातिया, धर्मी एव क्षेत्री के प्रतिनिधित्व को ध्यान म रखना पडता है। अत अपने सहयोगियों का चुनाव करते समय उसे फीच, कनाडा गर फीच रोमन कथोलिक जनता, बाठो प्रातो तथा वयूवेक क आग्ल मापी निवासियो का विशेष ध्यान रखना पडता है। सामायत तीन या चार मात्री फेच कनाडा के, चार या पाच ओ टोरियो के तथा नोवोस्कोशिया, पू तु सनिक, मानीटोबा, सरकचवान, अलबटा एव बिटिश कोलम्बिया का एक एक प्रति निधि मित्रमण्डल में शामिल किये जाते हैं। इसक अतिरिक्त प्रधानमंत्री प्रातीय धानना के प्रधानमं प्रया या काम स समा वे विरोधी दल क नेताओं को मन्त्रिमण्डल म आमि यत करता है। परम्परा के अनुसार मंत्री पद पर सीनेट के सदस्या की नियुक्ति आवस्यक नहीं है। परातु प्रधानमात्री को मोट्रियल या टारण्टा के विलाय हिता का विशेष ध्यान रखना पडता है। यह दोनो नगर वित्तम त्री के चुनाब को प्रमानित करते है। पनस्यरूप कभी कभी योग्यता की जपेक्षा करक भी मित्रया को नियुक्त किया जाता है। पलत डासन (Dawson) के अनुसार सहयोगियों क चुनाव म प्रधानम त्री नी स्वय ना इच्छा अत्यधिक सीमित होती है। बनाडा म यह एक स्वीरून अभिसमय है कि प्रत्यक्त प्राप्त का काद्रीय महित्रमण्डल में एक एक प्रतिनिधि जवस्य होना चाहिए,

बडे प्रान्ता के एक से अधिक प्रतिनिधि भी हो सक्ते है। अधिकाक्षत सभी मंत्री कॉम संस्था के सदस्य होते हैं।

समीक्षा—कनाडा की मित्रमण्डलीय व्यवस्था त्रिटिय प्रणाली पर आधारित है। कनाडा के सिवधान की प्रस्तावना के शब्दों मं, "कगाडा के प्राचा ने पुनाइदेड किंगडम (ग्रेट विटेन) के त्राउत के अधीन साधीय रूप म सगिठत होकर ग्रेट ब्रिटेन के समान सिद्धा तो पर सिवधान का निर्माण किया है।" वानो देशों की मित्रमण्डलीय व्यवस्था म पर्याप्त साम्य है यद्यापि दोनो देशों के मित्रमण्डलों के गठन मे अतर है। ब्रिटिश सस्तीय व्यवस्था के मुद्द सिद्धा त—राजनीतिक एकरसता, सामूहिक उत्तर-दाियत गोपनीयता एव प्रधानमन्त्री की प्रधानता—कनाडा की मित्रमण्डलीय व्यवस्था म भी पापे जाते है। ग्रेट ब्रिटेन की माति कनाडा मं नाममात्र एव वास्तविक काय-पित्रका का में प्रवाद के प्रदेश की निर्म सुमुश्ति के सिद्ध हुए विपा की हिन्द से बला जाता है। काशा में 1867 ई से आज तक केवल एक बार प्रथम विद्वयुद्ध काल में सपुक्त मित्रमण्डल का निर्माण हुना है। व्यवहार म राजनीतिक एकरसता कनाडा की ससदीय प्रणाली की एक महत्वपूण विदोयता रही है।

इगलैज्ड की भाति बनाटा म भी मिनमण्डलीय सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धात माय है। सभी मिनयों को एक दूषरे की राह्ययता एव सहयोग करना पढता है। सावजनिक रूप म वे अपन मतभेदों को व्यक्त नहीं करते हैं। मिनप्डल के निणयों से सतभेद रखने वाले मिनयों को अपने वस संत्यागपत्र देना पढता है। ऐसे विवादा को सतद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। मंत्री अपने त्यागपत्र में पद त्यागप्त के कारणा का उत्लेख कर सकते हैं एव प्रधानम नी को ससद म स्थित स्पष्ट करने के लिए बक्तव्य देने का अधिकार है। प्रधानम नी की मारा पर काम संस्तुत किया जाता है। इसस मिनमण्डल की स्थित काफी इड हुई है।

मित्रमण्डल के अधिवेशन गुप्त होत ह एवं निषया का भी गोगनीय रखा जाता है। गवनर जनरल मित्रमण्डलों के अधिवेशनों में नाम नहीं लेता है नेकिन समस्त सरकारी सूचना उसे प्रधानमंत्री हारा प्राप्त होती रहती है। कनाड़ा वा मित्रमण्डल रहा के प्रधानक नी हारा प्राप्त होती रहती है। कनाड़ा वा मित्रमण्डल रहा के प्रधानक वा चाल कर है। सिद्धानत मित्रमण्डल कॉम ससमा के प्रति उत्तरदायी होता है पर तुल्लवहार म ब्रिटिश मित्रमण्डल की माति वह की मित्रमण्डल की नाति वह की माति वह

कनाडा म प्रधानमानी की स्थिति के द्रीय है। डॉ वेनियस का जिटिस प्रधान मानी के सम्याद म व्यक्त यह मता कि 'प्रधानमानी सविधान का आधार स्तम्म होता है' कनाडा के प्रधानमानी के सादम मानी पूणत सत्य है। बनाडा व ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमानी की स्थिति एक सी ही है। वह देश का संवाधिक श्रतिखाली प्रधासक है।

वह मित्रमण्डल का निमाण एव विचटन करता है। वह देश व शासन का खामी है। परतु प्रधानमंत्री के पद का कोई निषिक आधार नहीं है। उसकी शक्ति पर नोई विधिक सीमा मी नहीं हैं। यदि प्रधानम त्री के पद की समाप्त कर दिया जात है तो देश का सम्पूष राजनीतिक समठन घरावामी हो जायगा । प्रधानमा क ह पा वर्ष भा पाने के प्रवासक प्रवासक प्रवासक प्रवासक क्षेत्र के मिन्न निमाण करता है पदाधिकारियों को नियुक्त करता है एवं मित्रमण्डल के सदस्यों के मध्य विमाना का वितरण एवं पुनर्वितरण करता है। खंदरमों के चयन म उसकी स्थिति निर्णायक होती है। वह किसी भी सदस्य को पदस्था क अथा न अथा न विदेश नीति के निर्माण में वह विद्यय रूप से उत्तरदायी होता है। गवनर जनरत एव म निमण्डन के मध्य वह एक कड़ी का काय करता है। वह मिन्नमण्डल की अध्यक्षता करता है और विवाद की स्थिति म निर्वायक मत दता है, विभिन्न मिन्यों के मध्य सम वय करता है विमागा का निरीक्षण एवं उन पर निय नण करता है। ससद में वह प्रवन दन का नता एवं ससद के बाद विवाद में वह वासन का श्रमुख प्रवक्ता होता है। मह बपूण विध्यका का ससद के समक्ष उसकी स्वीकृति पर ही रसा जाता है। वह गवनर जनरल का विशेष परामश्चरता है। महत्वपूष पदा वस उप राज्यपात, मित्रया आर्थिक की नियुक्तिया वह स्वयं करता है। डावसन (Dawson) के अनुसार, केनाडा के प्रधानमात्री वा काइ समकक्षा नहीं है। अंत समकक्षी म प्रथम हीन का कार्द प्रस्त ही नहीं उठता है। य बहु सूच की मीति है जिसके चारा थार अय नराप यमत रहत है। पर तुं उसकी स्थिति ससद म उसके दल की स्थिति एवं दल म उसक नेतत्व की स्थिति पर निमर करती है। प्रधानमंत्री का जितना हव नियत्रण अपन देल पर हाता है गासन म उसकी स्थिति उतनी ही हव होती है तथा अ ततागला उसकी स्थिति एवं शक्ति उसक् व्यक्तित्व पर निमर करती है।

आयर गणराज्य की कार्यपालिका ।

शावर स्वत त्र राज्य की मुक्य कायचातिका शक्ति राष्ट्रपति म निहित है। वह जनता होरा प्रत्यक्ष रीति स 7 वप क लिए निवाचित किया जाता है एवं पुत्र निवा 23 Dawson The Government of Canada p 221

24 एक तरंग समय र याद 1921 ई. म जीयरसकुत की ब्रिटिस साम्राज्य व जात भी स्थिति में स्पष्ट हिम्मा । 1921 द मा दिसम्बर साथ प भारा भाषात्रा मा स्थाप मार्था । आयरसण्डना स्थिति ननाडा एवं आस्तिया पा प्रभाव पा स्वरंद । तथा वथा था। आवरसम्बन्धाः स्थाव प्रभाव। एव वास्त्राधाः अति न य उपनिया। व समान ही थी तथ उसना नाम यस्तन्द भीवर स्वतं प्रभाव स्वरं तीव्य रम हिया गया। 14 जन 1937 ई मा आयरिस संसद न नमेन सीव पान का स्मिनार निया। ननना न भी ननमत सम्बद्ध होरा इस अपनी स्वीतृति प्रदान कर का तथा । वया स्वतंत्र एवं मध्यत् १४३/६ वा १वाव १११वाव १११ वा वावस्थाः । स्वतंत्र एवं मध्यत् तोवेतंत्व त्र घोषितं स्थि मया। नेवानं सेवियानं मं ब्रिटिस होता न माप सम्बन्धा ना कहीं नोई उत्तान ही दिया येगा। इस जनार पता न पता पत्रमा ना कहीं नोई उत्तान ही दिया येगा। इस जनार

चित हा सकता है । वह सदास्त्र सनाओ का भी प्रमुख होता है। डावल (Dail)—आव-रिण समद—इरा मनोनीत व्यक्ति को उसके द्वारा प्रधानम श्री नियुक्त किया जाता है तथा प्रधानम श्री के परामण पर वह अ य मित्रया को नियुक्त एव परच्छत करता है। वह निम्म सदन—डायस इरियान (Dail Eucann) या प्रतिनिधि सदन—के अधियेना आहृत नरता है एव उस विचरित करता है। ससद के दीना सदना द्वारा पारित विधे यका पर वह अपने हस्ताक्षर प्रदान करता है। उसे क्षमादान के अधियोग हिंग पर वह अपने हस्ताक्षर प्रधान करता है। उसे क्षमादान के अधियोग प्राप्त हिं। इष्ट को कम करने के उस अनियमित अधिकार प्राप्त हैं। सविधान द्वारा प्रदत्त अय विषयेन स्वाधि पर अपने हस्ताक्षर स्वाधियक के सिम्पति के विषये के सम्पति के विषये सम्पति सम्पति सम्पति के विषये सम्पति के विषये सम्पति के विषये सम्पति सम्पति के विषये सम्पति सम्पति सम्पति सम्पति के विषये सम्पति सम्पति सम्पति सम्पति के विषये सम्पति सम्पति सम्पति सम्पति सम्पति सम्पति स्वर्णे सम्पति सम्पति के विषये सम्पति सम्पति सम्पति सम्पति सम्पति स्वर्णे सम्पति सम्पत

यदि उच्च सदन (Second Eireann) सीनंट वा बहुमत एव हायल इरियान वे एव तिहाई सदस्य ससद द्वारा पारित विसी विधेयक को अस्वीकार करन की राष्ट्र-पति स प्रावना वरत है तो राष्ट्रपति को उस विधेयक को अनमत सपह के लिए प्रचा रित वरत या नवीन निर्याचन के आदेद जारी करने का अधिकार प्राप्त है। यह काउसल आफ स्टेट के लिए सात सदस्या को प्रनोनीत करता है।

सामायत बह मित्रमण्डल के परामक्ष पर ही काव करता है। कुछ अवसरो पर बहु काज काफ स्टेट से भी परामक्ष कर सकता है जिसम प्रधानम त्री, उप प्रधानम त्री, मुग्य यायाधीश, ससद के बोना सदन के अध्यक्ष, अटोर्ना जनरल एव कुछ अग सदस्य होते हैं। स्मरणीय है काज सल में के स्टट राष्ट्रपति को सहयोग प्रदान करती है, न कि उस पर नियाजण स्थापित करती है।

राद्रपति को डायस के बहुमत का समयन प्राप्त करने वाले किसी भी मि न मण्डल को विविद्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि प्रधानम भी खायल का विद्वास तो बुकता है और उसके विषयन की माँग करता है तो उसे ऐसी असवधानिक माँग को अस्वीनार करने का धिषकार है। आयरिख राद्रपति केंच राद्रपति से अधिकार है। आयरिख राद्रपति केंच राद्रपति केंच को है। की किन अभिरिको राद्रपति की तुलना स उसकी सित्तमों कम है। प्रधानम नी उसके प्रति उत्तरदायों नहीं होता अपितु लोकप्रिय प्रधानम नी तो उसका प्रतिस्पर्धी हो सकता है। महान आयरिख राद्रप्रदानी नेता डी अलरा दीषकाल तक राद्र्य

क्षायर-मणराज्य का जम्म हुआ। आयरलण्डना प्रमुख राष्ट्रवादी नेता, डी वलरा, क्रिटेन से पूण सम्ब प विच्छेद का समयक या। उसने क्रिटेश राजा के नाम प्र रापय लेने से दुष्कार कर दिया। इस पर पनतर जनतर को प्रत्याग के विच् वाच्य क्रिया गया तथा एक ग्रामीण को राष्ट्रपति बनाया गया। 1948 ई म ससीय विधि के द्वारा आयरलेण्ड न ब्रिटेन से पूणत सम्बध्ध विच्छेद कर विदा है।

³⁹⁰ | बाधुनिक शासनत[्]न

पति रहा था। पत्तस्वरूप इस पद का विश्वास्ट महत्व हो गया है। भागरिस प्रधानम गी तिहरा प्रवासम् तो की माति अपने सहयागियों का चुनाव करता है। वही राष्ट्रपति को ससद क विघटन का वरामश देता है। राष्ट्रपति को ससद को आहुत करने का गरि त्रधानम नो द्वारा परामद्य नहीं दिया जाता तो राष्ट्रपति को स्वय ही सबद को जात करते का अधिकार है। निर्वाचन या संसद म पराजित होने के पश्चात यदि प्रवात म त्री अपन पद स त्यागपत्र प्रस्तुत गहीं करता है तो राष्ट्रपति उसे पदब्युत कर सकता है।

आयरिश राष्ट्रपति अमरिकी राष्ट्रपति की मौति प्रत्यक्ष रीति हे निर्वाचित होता है। अत वह जनता का प्रतिनिधित्व करता है। परस्तु आयरलैंग्ड म शक्ति पृत्वकरण का सिद्धा त माय न होने क कारण आयरिश राष्ट्रपति अमरिकी राष्ट्र पति की प्रतिमूनि नहीं वन मका है।

आस्ट्रेलिया की कायपालिका कनाडा के समान ही है। इसका प्रमुख कारण यह है कि सास्ट्रिया भी कनाडा की माति ही ब्रिटिश साम्राज्य का अग पा एव होता ही स्वत नता प्राप्ति के पश्चात ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के बतबत औपनिवेधिक राज्य वन रहे और आज भी उ होने राष्ट्रमण्डल से सम्ब थ विच्छद नहीं किया है। 1900 ई को कामनवत्य आफ आस्ट्रेनिया एक्ट (The Commonwealth of Australia Act 1900) जास्ट्रेलिया का संविधान है। यह 1 जनवरी, 1901 ई से लागू हुआ है।

जास्ट्रेलिया की कायपालिका के तीन अग हैं—नाजन, गवनर जनरस तथा मिनमण्डल । नाउन एव गवनर जनस्व नाममान की कायपाविका है सिनमण्डल वास्तविक या राजनीतिक कायपालिका है। आस्ट्रेलियन कायपालिका का स्वरूप सह वीय है। काउन एव गवनर जवरल

सविवान द्वारा कायपालिका शक्ति काउन—राजा वा रानी—म अधिद्वित की गयों है जिसका प्रयोग रानी क प्रतिनिधि के रूप म गवनर जनरत करता है। बिटिस रानी इंगलण्ड की रानी हीन के नात आस्ट्रेलिया की रानी नहीं है अपितु पुषक रूप म बहु ऑस्ट्रेलिया की रामी है। गवमर जनरत को बास्ट्रेलिया की सरकार क प्राम्भ पर काउन द्वारा नियुक्त निया नाता है अोर उसी ने प्रामस पर उस सापस 25 अनुच्छेर 61

26 1924 ई से पूज गवनर जनरत को ब्रिटिस मि त्रमण्डल क वरामस पर ब्रिटिस पाठन के कि जिल्ला की ब्रिटिस मि त्रमण्डल के वरामस पर ब्रिटिस भारत होरा निमुक्त किया जाता था। 1926 ई. म संस्कृति के प्रधानन पर किया वाता था। 1926 ई. म संस्कृति रिपोट म यह ार्था वर्ष । १९४७ । १४ । ४४० हम वालकार । १४८० हम वालकार । १४४० हम वालकार वि कर का 1930 ई के ग्रामानीय सम्मातन में यह निवचय निया गया कि गार जारत की तियुक्ति होमीनियन मन्त्रिया व परामन पर ही होनी सहिए।

भी युलाया जा सकता है। वास्तव म यह सासन द्वारा मनोनीत अधिकारी है अत उसका कायकाल प्राउन के प्रसाद पय त है। यवनर जनरल क्राउन का प्रतिनिधि है। ²⁷ जत आस्ट्रलिया को वह मुख्य कायपालिका है।

गवनर जनरल आस्ट्रेलिया की सक्त सनाओ का प्रधान सेनापित हाता है। वह यहुमत दल के नेता को मिश्रमण्डल बनाने के लिए आमित करता है एव उसे दायप दिवाता है। उसे राप्ट्रीय सम्बद का आहून, स्थिगत एव विघटित करने के अधिकार प्राप्त है। विस्त विपयम का समय के समय प्रस्तुत करने से पूव यह उन्हें प्रमाणित करता है। ससद हारा विधेयका के पारित किये जाने पर उन्हें गवर्नर जन एक की स्थाजित के लिए प्रस्तुत किया जावा है और उन्हें स्थीजित प्रदान करने अथवा अपने मत के साथ पुनविचार हेतु ससद को लीटान का उसे अधिकार प्राप्त है। गवनर जनरत किसी मी विधेयक को रानी के विचाराय रोक सकता है। भे वह उच्च पाया लय के पायाधीशा को नियुक्त करता है एव समद के दोनो सदनो के अनुमोदन पर उन्हें परक्षुत कर सकता है। यदि ससद के दोनो सदन—सीनट एव प्रतिनिधि आयार—
म किसी प्रदाप काई मतभेद उस्पत हो जाता है तो यवनर जनरल दोना सदनो के विषयन का अदेश दे सकता है।

लेक्नि गवनर जनरल इन शक्तियों का प्रयोग मित्रमण्डल की सलाह पर करता है। वह इगलैण्ड के राजा की माति सवधानिक अध्यक्ष है। वह स्वविवेद एव स्वत प्रताप्तक आवरण नहीं करता। मित्रमण्डल के परामश पर ही वह नियुक्त किया जाता है एव वापस में बुलाया जा सकता है, फलत उसकी स्थित कमजोर हो। गयी है। अत वह मित्रमण्डल के समका शक्तिहीन है। वह बिटिश काउन की सरकार का अभिकर्ता है। शहरे हिन्दी काउन की सरकार का अभिकर्ता हो है। आस्ट्रेलिया। मिटिश हिनों के सरकाय हेतु एक हाई कमिश्तर रहता है। गवनर जनरल की स्थित रबड की मोहर के सहस्थ है।

मदिमण्डल

यह देश की राजनीतिक एव वास्तविक कायपालिका है। सिवधान ने सधीय कायकारिणी परिषद को ही कायपालिका अधिकारी के रूप में भा यता दी है एव इसका काय गवनर जनरल की परामक्ष देना है। अ सिवधान म जहां कहीं सपरिषद गवनर जनरल का प्रयोग किया गया है, उसका आश्रम कायकारिणी परिषद से है। ३१

²⁷ धारा 2।

²⁸ धारा 68।

²⁹ धारा 58, 59, 60 ।

³⁰ धारा 62 ।

³¹ इसकी बैठक मं गंबनर जनरल अध्यक्षता करता है एव सदस्यगण उसके प्रसाद-पय त जीवन मर अपने पदो पर वने रहते है।

इसके विपरीत मित्रमण्डल एक बनीपचारिक सस्या है एव इसका कोह निश्चित विधिक वाधार नहीं है। यह कनाडा और निटेन के मी त्रमण्डल की माति अभिसम पर बाचान्ति है। फिर भी यह शासन का सर्वाधिक शक्तिसाती कायपासक अन है। मित्रमण्डल म प्रधानम् त्री व अतिरिक्त अय मत्री भी होते हैं। उनम प्रमुख है वदेशिक मामल आ तरिक मामले वित्त स्वास्थ्य च्वोग, ध्यापार धीमा शुल्क, क्षे नोंसेना एव वायु विभागा के मनी तथा एटानी जनरल एव पोस्टमास्टर जनरल शारम्म स मित्रवा की सरवा 7 हे अधिक मही हो सकती थी (धारा 65) किन्तु अव वढ कर 28 तक पहुँच गयी है।

पत्यक म नी ससद के दोनों सदनों मं सं किसी एक सदन का अनिवायत मदस्य होता है। यदि कोई मात्री ससद का सदस्य नहीं है तो पर प्रहण के तीन मास के तीतर उस सम्स्यता प्राप्त कर तेना आवश्यक है। विद्यान्त म म नी गवनर जन रेल क मसाद पय त पदाल्ड रहते हैं। कि तु व्यवहार म उहाँ प्रतिनिधि सदन के सदस्य कं बहुमत का विस्त्वास एवं समयन प्राप्त होना चाहिए । समी मंत्री नायकरिणी परिपद क पन्न सदस्य होते हैं।

जास्ट्रलिया म भी प्रनानम नी मिनमण्डल की रचना करत समय समी प्रदेशा को प्रतिनिधित्व देन का प्रयत्न बरता है। मिनमण्डत म स्थान प्राप्त करने के लिए प्र साज्य बत्स एवं विवटोरिया राज्य कं मध्य सर्वेव प्रतिद्वद्विता होती रहती है। यह अमिसमय विकासित हुआ है कि मित्रमण्डल म सभी प्रदश्ता के प्रतिनिधि होने चाहिए। यदि क्षम दल का बहुमत होता है तो उस दल का प्रधानम त्री अपन मत्रियों के प्रया म स्वतंत्र महोते होता अपितु उसे धमदलीय नेताओं को एक तम् समिति द्वारा वृत्त गय मा त्रा को मिनमण्डल म स्थान देना पडता है। ससद वी थमदसीय समिति सम्मावित मित्रयो क नामो की मुची तैयार करती है एवं इसी मुची म सं संसद म बहुमत प्राप्त श्रमदलीय नेता अपने मित्रयो का चयन करता है। अत यह सम्भद है कि उस ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करना पढ़े कि ह वह प्रसद न करना हैं। ऐसी स्पिति म स्पत्तिगत रूप से मंत्री भी प्रमानमंत्री ने प्रति मस्ति नहीं रसते हैं बयोक्ति वे यह समस्त हैं कि उनकी देनीय नताओं की देपा एवं सहयोग से चुना गया है। निर्याचन की इस रीति का एह अय दुष्परिणाम भी है। स्वीय समिति कमी क्यानमात्री को जपना समयन प्रदान करना वद कर देती है, प्रतस्वरण राजनीतिक अस्थिता उपम हो जाती है। 1901 इ.स. 1943 ई. तम के सान म बास्तुतिया म 24 मित्रमण्डल तब 13 त्रयानमत्री वन थे जबकि इसी बास म र नाहा म प्र मन्त्रिमण्डल एक 5 प्रपालमात्री हुए हैं। धमण्लीय प्रपालमात्री नी देशीय नेताओं हारा ही चुना जाना है। इसन बितिरक्त समनेय नासन भी अब विन्यता— भारतीयता— रा भी आस्त्रुनिया म पूच पात्रत नहीं थिया बाता। इंबट ही मुस्स

सूचनाएँ ससद म प्रस्तुत करने के पूच ही प्रकट हो जाती है। यही मित्रमण्डल च्य महत्वपुण निणयों के सन्दम मंभी सत्य है।

प्रधानमानी ससद के निषटन की माग करने के पून अपने सहयोगियों से परा करता है। 1914 ई के पून 3 अवसरों पर गवर्नर जनरल ने ससद के विषटन राग को अस्वीकार कर दिया था।

नम त्री

बह मित्रमण्डल का अध्यक्ष होता है। श्रमदलीय प्रधानमित्रयों को छोडकर देलिया के प्रधानमानी की स्थिति विटिश या भारतीय प्रधानमानी जसी होती श्रमदलीय मित्रमण्डल के सभी मानी व्यवहार म दलीय समिति के प्रति (दायी होते हैं, न कि प्रधानमानी के प्रति । अय दल के प्रधानमित्रया के सादम ह बात सत्य नहीं है। आस्ट्रेलिया मे प्रधानमानी तानाशाह नहीं होता। उस्पत्त कालीन अनुमन, दल ये उसकी स्थित, ससद म उसके दल की स्थिति आदि देश जनतीति एक श्रासन में उसे महत्वपूण स्थान प्रदान करते है। प्रधानमाणी की वास्त- स्थिति उसकी क्षमता, योग्यता, वृद्धिसता एव व्यक्तित्व पर निमर करती है।

ब्रिटन की माति ही आस्ट्रेलिया म समसीय प्रणाली की तीव आलोचना की है। कुछ आलोचको का मत है कि आस्ट्रेलिया म मित्रमण्डल के निणयों में कारात विलम्ब एव अस्थिरता होती है। म मीगण लोकसेवको के हाथों में रवड नीहर के समान हैं। मित्रमण्डल ऐसे विमामाब्यकों का समूह है जो अपने स्थायी शारियों के निणया को स्थीकृति प्रवान करके ही सपुट हो आता है। ससद एव एक सकत वाही के हाथा में मित्रमण्डल वादी-असा है। आस्ट्रेलिया के राज कि जीवन में मित्रमण्डल में सामाजिक आवस्थलता एव उपरोक्त दोयों रिमाजन हेत् सखीधन की चर्चा होन सगी है।

यूगोस्लाविया की कार्यपालिका

यूपोस्लाविया साम्यवादी देश है। माच 1945 ई म माझल टीटो ने द म समाजवादी जाति की सफलता के परचात वहा नवीन शासन की स्थापना हुई नवीन सबियान 31 जनवरी, 1946 ई की लागू हुआ या। कायपालिका शक्ति राज्य के राष्ट्रपति एव सधीय कायकारियो परिवद (Federal Execution Incil) में निहित है। यूगास्लाविया की कायकारियो का स्वरूप वाह्य रूप म रीय सा प्रतीत हाता है। लेकिन यूगास्लाविया म एक्टलीय व्यवस्था है अत व्यवहार हाँ साम्यवादी दल का शासन है।

पति

यूपोस्ताविया गणराज्य के राष्ट्रपति का कायकाल चार वप है। यह फेडरल बलो द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ³² यह कवल एक बार पुन निर्वाचित

अनुच्छेद 221

हो सकता है पर जु माराल टीटो पर अवधि सम्बंधी यह सीमा लागू नहीं होती। राष्ट्रपति के कायकाल को समाप्ति के एक माह पूत्र फहरल असेम्बली राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। पंडरत असेम्बली के तीस सदस्या हारा स्वेच्छा से या प्रगोस्नाविय ने श्रीमक्ता क समाजवादी सघ (alliance) की संघीय समिति द्वारा नाम प्रस्तावित किय जान पर राष्ट्रपति पद के लिए नाम प्रस्तुत किया जाता है। इन तीस सदस्य प्रस्तावका म स 5 शस्तावका को प्रत्येक गणराज्य का निवासी होना बाहिए एक 15 प्रस्तावन संघीय विधानमण्डल के सदस्य होने चाहिए।²⁴ जिस प्रत्याक्षी को संघीय विधान भण्डल के संदर्भा का बहुमत प्राप्त होता है वह राष्ट्रपति निर्गोचित कर लिया जाता है एव त पश्चात सपय ग्रहण करता है। वह सभी सदनों के समुक्त अधिवेशन मे निर्वाचित क्या जाता है।

पूल सर्विधान मं उपराष्ट्रपति की भी व्यवस्था थी। जस राष्ट्रपति की अनु पहिन्ति में उसक कतव्य सम्पान्ति करने का अधिकार प्रवान किया गया या। उसका कायकाल चार वप था एव वह राष्ट्रपति की माति ही निर्वाचित क्रिया जाता था। परंतु पाचव सबधानिक संबोधन (1967 ई) हारा उपराद्यांत का पर समाप्त कर दिया गया है। ³ अंत राष्ट्रपति की अनुपस्पिति म फ़ैडरत असेम्बती का अध्यक्ष उसके कार्यों को सम्पादित करता है।

राष्ट्रपति के काय एव राक्तिया—राष्ट्रपति देश एव विदेशा में यूगीस्ताविया के समाजवादी सभीय गणराज्य का प्रतिनिधित्व करता है। वह पूर्वोत्त्वादिया की सहास्त्र सनाश्चा का सेनापति है। ^इ उसी के प्रस्ताव पर सधीय कायकारिकी परिपद का अध्यक्ष तमीय समा द्वारा निर्वाचित किया जाता है। कामकारियी परिपद के प्रधान क प्रस्ताव पर उसक अ व सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। ³⁷ वह संघीय विधियो को आगापित करता है राजदूतो एव जय राजनियक अधिकारियो को नियुक्त करता हैं उहें बारत हुता सबता हैं विदेशी राजदूता स परिचय पत्र प्राप्त करता है अत रिष्ट्रीय सिध्या को अनुमोदित करता है एवं सम्मानसूचक पदिवर्ग प्रदान करता है तथा सधीय कायकारिणो परिपद के निषयों को आसापित करता है। यह पूर्णस्ताचिया है सबधानिक यायालया के यायाधीको एव उसने अध्यक्ष का नाम प्रस्तानित करता

³³ अनुबंधेर 220 मादाल टीटो को 1964 ई म बीबो बार राष्ट्रपति बुना गया ंत्रपुष्ट 220 बाहाल टाटा का 1964 इ.स. चाया बार राष्ट्रपाठ पुण गा था। अब मामल टीटो को जीवन भर के लिए राष्ट्रपति चून लिया पुण गा वे जीवन भर के निए साम्यवादों रल के अध्यक्ष भी चुन लिया गा है एव अनकोठ २२। 34 अनुच्छेद 221 35 अनुच्छेन 223 224 36 अनुच्छ> 215

³⁷ अनुच्छ- 216

है तथा उपसेतायित नो नियुक्त एव पदच्युत करता है। सधीय परिषद (Council of Federation) के सदस्यों के निर्वाचन एव पदच्युत करते सम्बच्धी प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। सधीय विधिया सम्बच्धी फीजदारी अपराधा के सम्बच्धी प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। फेडरल असेम्बली के समावसान-काल में युद्ध को घोषणा करता है, आवर्यक कमचारिया एव अधिकारियों की नियुक्ति करता है। युद्ध को घोषणा करता है, आवर्यक कमचारिया एव बायित्वों को सम्यादित करता है। युद्ध को चाय युद्ध को आव्यक्त कर्या अधिकारा एव बायित्वों को सम्यादित करता है। युद्ध काल या युद्ध को आव्यक्त को स्थिति म सधीय कायकारियों परिषद द्वारा मांग विये जाने पर सधीय सभा के अधिकार क्षेत्र सम्बच्धी मामला के सम्बच्ध य आवेद्ध दे सकता है जिनका विधि के सहस्य महत्व होता है। ऐसे आवेद्यों को राष्ट्रपति सधीय सभा के समक्ष अधिवान के आरम्य होन पर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करता है। वह युद्ध काल म नागरिक अधिकारों को देश की सुरक्ष के लिए निलम्बित कर सकता है। अधीय कायकारियों परिपद द्वारा पारित आवानित्या एव सामाय राजनीतिक महत्व के अ य विनियम को प्रकाशित होने के पूत्र रोकन का अधिकार राष्ट्रपति को है। इस प्रकार रोके गये विनियम या आनानित सम्बच्धी विवाद को राष्ट्र आतिवा को सभा के समक्ष दुरत्त ही उपस्थित किया जाना चाहिए। **

राष्ट्रपति अपन कार्यो एव वापित्वा के लिए सधीय समा (Federal Assembly) के प्रति उत्तरदायी होता है। उसे पद सम्ब धी अनेक उ मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ' यह राष्ट्रपति का दायित्व हैं कि सधीय समा को आ तरिक एव वैदेशिक समस्याओं के सम्ब ध में वह निर तर सुचित कर एव विशेष मामले की समा म विचाराध उपस्थित करे। ¹¹ वह राज्य की नीतिया एव राजनीतिक, कायपालक एव प्रशासनिक अगा के कार्यो पर विचार करने के लिए सथ परिषद का अधिवसन आहृत करता है। सथ परिषद का अधिवसन आहृत करता है। सथ परिषद के सदस्यों का निवांचन राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर ही किया जाता है लेकिन 9वे सवैधानिक संशोधन हारा सधीय परिषद के इन दायित्वा को राष्ट्रजाति समा को हस्ता-तरित कर दिया गया है। ' सभ परिषद एक परामस्वस्यों निकाय है।

राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष है एवं संघीय घासन में उसके विशेष दायित्व एवं कतव्य है। वह अपने सर्वेषानिक अधिकारों का स्वतं त्रतापूवक प्रयोग करता है। संघीय कायकारिणी परिषद से उसके विशेष सम्बन्ध होते है। पर तु वह कायवालिका

³⁸ अनुच्छेद 217

³⁹ अनुच्छेद 218

⁴⁰ अनुच्छेद 219

⁴¹ अनुच्छेद 222

⁴² अनुच्छेद 224

596 | आधुनिक शासनतः त्र

का प्रधान नहीं है। राष्ट्रपति की बहायता के लिए उपरोक्त उल्लिखित एक राजनीतिक निकाय—राम परिपद (Council of Federation)—का निर्माण किया गया है। सघोय कायकारिको परियद

संविधान द्वारा सधीय कायकारिणी परिपद को कायपालक शक्तियाँ प्रदान की गयो है। यह फेडरल असेम्बली हारा निश्चित मूलभूत विद्या तो पर आयारित नीति को कियानित करती है। ध इसका एक अधान एवं अस सदस्यमण होते हैं। वे सधीय समा द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। प्रधान के नाम को राष्ट्रपति प्रस्ताबित करता है एव वह संघोष समा का सदस्य होता है। ध वरिषद के प्रधान डारा उसका प्रतिनिधित किया जाता है तथा उसके निषयो एव नीति को किया बित करने के लिए वह हर प्रकार का प्रयत्न करता है। किसी गणराज्य या 5 सवस्या द्वारा माग किये जाने पर राष्ट्रपति को परिपद का अधिवेदान आहुत करने का अधिकार प्राप्त हैं। यह विभिन्न प्रशासनिक अमो के कार्यों में तम इय स्वापित करता है। ^ध परिवद अपने कार्यों के लिए संघीय समा के प्रति उत्तरदायों होती है। परिपद ब्रास प्रन्तावित किसी भी विधयक या विनियम के तिविधान विरोधी होने पर तथीय समा उसे अस्थीकार कर सकती है। परिवद को अपने क्षेत्राचिकार सम्बन्धी वाधित्वाको वतमान सविधान एव विधियो की सीमा के अ तगत ही पालन करना चाहिए। अ परिपद को निर तर अपने काय क तम्ब ध में तथीय तमा को सूचित रखना चाहिए। कायकारिची परिपद सथीय तमा व किसी भी तदन को निसी विधेयक पर विचार न बरने या उसे पारित न करने सम्बधी आदेत है सकती है। संधीय समा परिवद के उचित विचारा के विपरीत यदि विसी विधेयक को पारित कर देती हैं और वह यह अनुमव करती है कि उस विधयक को वह निया वित न कर सकेमी य तो कायकारिणी परियद सामूहिक रूप म त्यापपत्र प्रस्तुत कर सकती है।

गणराज्यां की कायकारिकी परिपदों ने अध्यक्ष, संपीय कायकारिकी के सचिव एवं सधीय समा द्वारा प्रस्तावित सधीय अधिवारीयण कायकारिणी परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। ध संधीय सदन को अपने किसी एक सदस्य को परिपद ना प्रयान या तदस्य निर्वाचित करने का अधिकार प्राप्त है। परिषद क प्रधान को किसी सदस्य 44 अनुकर्न 226

⁴⁵ अनु च्दे≈ 230

⁴⁶ अनुच्छद 231

⁴⁷ जनुन्ध्द 232

⁴⁸ अनुरछ≈ 226

सो पदच्युत करन एव उसके स्थान पर किसी नवीन सदस्य को निर्वाचित नरने ना प्रस्ताव प्रस्तुत करने का भी अधिकार प्राप्त है। परिषद क प्रधान को पदच्युत करने या परिषद के बहुसम्यक सदस्या के त्यागपत्र ना अब सम्पूण परिषद का त्यागपत्र होता है। ¹⁹ कायनारिणी परिषद क द्वारा निम्नतिखित नतव्य सम्पादित किय जाते हैं

- आत्तरिक एव वदशिक नीति का निमाण, नीतियो एव विधिया तथा सधीय यजट, सामाजिक योजना एव सधीय समा के अप विधेयका का फिया वयत ।
- (2) सपीय समा म विधेयका को प्रस्तुत करना एव अन्य प्रस्तावित विधेयका पर अपनी राग प्रकट करना।
 - (3) सघीय बजट एव सामाजिक योजना का निर्माण ।
- (4) सधीय समा द्वारा पारित विधियों के अधीन उनके किया वयन हेतु निणय, आदेदा एव निवेंदा देना ।
- (5) सधीय प्रशासनिक निकाया के आत्तरिक सगठन सम्ब धी सामा य सिद्धा तो को निर्धारित करना ।
- (6) सघीय सभा की विधिया के अधीन सचीय प्रशासनिक निकायो सम्ब धी निणय करना ।
- (7) सचीय विधि विरोधी सधीय प्रशासनिक निकाया द्वारा पारित नियमों को निष्प्रमानी घोषित करना।
 - (8) अत्तर्राष्ट्रीय सचिया का अनुमोदन।
- (9) सर्वोच्च यायालय के प्रधान एव यायाधीक्षा तथा आर्थिक यायालय एव सधीय पब्लिक प्रोसीक्यूटर के निर्वाचन एव पदच्युत का प्रस्ताव करना ।
 - (10) प्रशासनिक एव अप अधिकारियों की नियुक्ति करना।
 - (11) सधीय विधियो तथा कुछ सधीय कोषा का प्रबन्ध करना।
 - (12) सधीय विधिया द्वारा सीप गये दायित्वो को सम्पादित करना ।

कायकारिकी परिषद के विदोप दायित्व हैं। वह सपीय समा के प्रति उत्तर-दायों होती है। इसके सदस्य सभीय समा के सदस्य होते हैं। कायकारिकी परिषद की स्थिति मन्त्रिमण्डल जसी होती है। मन्तिमण्डल की माति इसका एक प्रधान होता है। यदि कायकारिकी परिषद की नीतिया एक कायपद्धति सधीय समा द्वार स्वीवन राज्य की जाती ता वह सामूहिक रूप से पदस्याय कर देती है। इन उपचाम से यह प्रतीत होता है कि यूगोस्लाविया के बतमान सविधान म ससदीय कायपालिका के इस मूल सिद्धात की मा यता दी गयी है कि कायपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी

⁴⁹ अनुष्छेद 227

⁵⁰ अनुच्छेद 228

होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व के विद्वात को भी मा यता दी गयी है। परनु एन देलीय व्यवस्था के कारण इसमें स देह हैं कि परिषद मित्रमण्डल की माति कारण करती है या नहीं । एकदलीय व्यवस्था में कठोर दलीय निय त्रण का हीना स्वामाविक है। इसके अतिरिक्त यूगोस्लाविया म राष्ट्रपति नाममात्र का अध्यक्ष नहीं है। उस ब्यापक शक्तिया प्राप्त है। वह राज्य व कायपालिका रोनो का अध्यक्ष होता है। मामल टीटो व्यपन देश के लोकप्रिय नेता है एव व्यवहार म सत्ता जनम के जित है। राष्ट्रपति हो जन्नाधिकारियों को नियुक्त करता है। वह ग्रेट ब्रिटेन और मारत शादि संसदीय देशा की मांति नाममान का अध्यक्ष नहीं है। संधीय कायकारिणी परिपद के प्रधान की त्यित प्रधानम त्री जसी होती हैं। लेकिन उसकी स्थिति बिदिश प्रधानमत्त्री की अपेक्षा पाचने गणराज्य के के च प्रधानम नी जसी है। माशल टीटो विस्त के प्रक्ति साली राज्याच्यक्षों में हें हैं परतु यूगोस्लाबिया के राष्ट्रपति की शक्ति सवधानिक सीमाओ से मर्यादित है। विधानमण्डल को काफी व्यापक शक्तिमाँ प्रदान की गयी हैं।

नेपाल की कायपालिका म तीन अग है (1) सम्राट, (2) राजसमा, एव (3) मिन वरिषद (Council of Ministers)। नेपाली कायपालका की विश्वपता गर् है कि वह न तो ससदोय है बोर न अध्यक्षात्मक, अपितु वह इन दोना के निश्रण का परिणाम है। सम्राट

नेपाल म सम्राट शासन शक्ति का लोत है। वह ब्रिटिय राजा की भीति वतानुसत राजा है। ¹² राज्य की सावभीम सत्ता नैपाली नरेस म निहित है ¹ और वह निटिस राजा की मीति सबैधानिक बध्यक्ष नहीं है, अपितु वास्तविक प्रधान है। यह राज्य व शासन दोनो का लव्यक्ष है। नेपाल का सविधान सम्राट द्वारा प्रदत्त उपहार है। सिवधान की प्रस्तावना के अनुसार 'में सम्राट महें द्वीर विकास सह देव निहित सावमीम सत्ता एव विशेषाधिकारों के द्वारा सविधान की अधिनियमित एव उदयोषित करता है।' . सम्राट की शक्तियाँ पर्याप्तत विस्तृत है

(1) कापपासिका शक्ति—समस्त नायपालिना सक्ति सम्राट म अपिट्टित है। इसना नयोग वह स्वय अथवा मित्रयो या अधीनस्य कमनारियो द्वारा करता है।

⁵¹ Att 21 म उत्तराधिकार सम्बाधी नियमा का उत्तेस हैं। सम्राट को उत्तरा-राप का प्रवाधिकार सम्ब्र पा नियमा का उल्लंस हूं। सम्राट का प्रशास के परिवर्तित संचातित एव समाप्त करत का विधार है। सर्विपान के बहुकार सम्राट पृथ्वी नरावण पाह या वाज एव आप सस्मृति हा पावधान क अञ्चल संभाट पृथ्वा न रायक काह ने तया हिंद्र पर्मावतस्यों ही नेवात ना सम्राट हो सनता है। 52 Article 20 (2) of the Fundamental Law of Nepal

राज्य एव द्वासन के समस्त काम सम्राट के नाम पर किये जात हैं और किसी यायास्य म इन काम को चुनीती नहीं दी जा सकती । वह देश की सशक्त सेना का
सर्वोच्च अध्यक्ष होता है। वह विदेशी राजदूता का स्वागत करता है एव उनके
परिचय पत्र प्राप्त करता है, नागरिका एव अप व्यक्तिया को सम्मान एव उपाधिया
प्रदान करता है, विदेशा स सिध्यों करता है एव युद्ध की घोषणा का उसे अधिकार
ह । वह मित्र परिषद का प्रधान होता है तथा उसके अधिवेशाने की अध्यक्षता करता
है । मित्र-परिषद के अध्यक्ष एव उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है। मित्रपरिषद उसके
प्रति उत्तरदायों होती है और उमके प्रसाद-पयन्त पदाच्छ रहती है। सम्राट सभी उच्च
पदाधिकारिया जसे महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष एव सदस्यों आदि
को नियुक्त करता है।

- (2) विधायो प्राक्ति—वह राष्ट्रीय पचायत के अधिवेशन में मारण करता है । यस तासन की नीतियो का उन्लेख करता है । उसके अधिवेशनो को आहूत करता है । एव उह स्थिति करता है । वह राष्ट्रीय पचायत को सर्वेश भेजता है तथा पचायत के 15% सदस्यों को मनोनीत करता है । राष्ट्रीय पचायत द्वारा पारित सभी विवेयक उसकी स्वीकृति के पदचात ही विधि बनते हैं । विधियों की स्वीकृति सम्ब थी उसकी शिक्त कि ति है । उस अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है । ये अध्यादेश पार्टीय पचायत की विधि को भीति ही प्रभावकारी होते हैं । विस्त मभी के अति रिक्त राष्ट्रीय पचायत की विधि की भीति ही प्रभावकारी होते हैं । विस्त मभी के अति रिक्त राष्ट्रीय पचायत की अधिकार को सीति ही प्रभावकारी होते हैं । विस्त मभी के अति रिक्त पार्टीय पचायत की अधिकार। को सीमित करने वाले विधेयको को उपस्थित करने के सिए सम्राट की पुन-स्वीकृति आवश्यक होती है ।
- (3) "याधिक शक्ति—वह याय का स्रोत है एव सर्वोच्च यायालय के याया भीको एव महा यायवादी की नियुक्ति करता है। वह किसी भी दण्ड का क्षमा, कम या स्यगित या परिवर्तित कर सकता है एव याय सिमिति के परामदा पर सर्वोच्च "यायालय को अपने निणय पर पुनर्तिचार का आदेश दे सकता है।
- (4) सकटकालीन सक्ति—सम्राट को यदि यह विश्वास हो जाय कि युढ, बाझ जानमण एव आत्रिक अद्याति के कारण देश में सकटकालीन स्थिति उत्यम्न हो। गयी है तो यह सम्यूण देश या उसके किसी माग म सकट कालीन की पोवण के फलस्वरूण यविधान की सकटकालीन आराओं को छोड़कर होप सभी धाराएँ निकम्बत हो जाती हैं और सम्राट राष्ट्रीय पचायत, शासकीय सहयाजी वया अधिकारियों के अधिकारों को स्वय वहन कर लेता है। सकटकालीन स्थित को सम्राट एक अप्य उदयोषणा ढारा समाप्त कर सकता है। सम्राट के द्वारा हो सकट काला की स्थिति को सम्राट कर के सम्ब ध म अतिम निगम किया जाता है। यदि वह जीवत ममके सा इस सम्ब भ में राष्ट्रीय पचायत एव राजनमा की जाता है। यदि वह जीवत ममके सा इस सम्ब भ में राष्ट्रीय पचायत एव राजनमा की

600 | अधुनिक शासनत न

स्यायो समितिया से परामस्य कर सकता है । अविशिष्ट शक्तिया सम्राट म अस्यायो हर स निहित है।

मुल्याकन—नेपाल का सम्राट सिद्धा त एवं व्यवहार म राज्य का सर्वोच्च सत्ताचारों है। वह राज्य शक्ति की के त्रीय चुरी है जिसके चारो तरफ समूण शासन तत्र प्रमता है। वह सम्प्रमु सता का बादि सोत है। सविधान उसके हारा अधि नियमित एव उरमीपत है। मित्रमण्डल उसके प्रति उत्तरस्यो होता है। यह अमे रिकी राष्ट्रपति की मंति राज्य एवं शासन का अध्यक्ष है और बिटिश समाट की माति वशानुगत रोति सं नियुक्त होता है। समस्त राजसता का प्रयोग समाट के नाम पर किया जाता है। सि त्र परिपद के सदस्य उसके अधीतस्य सक्क होते हैं। बहु असे रिक्षी राष्ट्रपति की माति मन्त्रिमण्डलो के अधिवेशमों की अध्यक्षता करता है। उसकी स्विति ब्रिटिश सम्राट एवं अमेरिकी राष्ट्रपति दोना से ही थेस्ट है। ब्रिटिश सम्राट की मति नेपाल गरेश की भी दोहरी स्थिति है—(1) व्यक्ति के रूप म, एव (2) तस्था के ह्यू म । तस्या के ह्यू म नेपाल गरेश की बुलना जिटिस संग्राट से की जा सकती है। वैकिन वह निर्देश संभार की मानि नाममाय का अध्यक्ष मही है। यह राज्य व हासन दोना का प्रधान है। ब्रिटिश सम्राट राज्याकाक्ष होने के कारण शर्म पाननीति में ऊपर होता है पर तु नेपाल नरस के सामन का बास्तविक अध्यस होने के कारण देलात राजनीति म फैसने की असका है। मास्तीय राज्यति की मीति वह संपपा-निक अध्यक्ष मही है। मारतीय सविधान के अनुसार सकटकातीन शक्तियों का भी प्रयोग वे हीय सासन (ससद) म अधिप्टित है। अवसिष्ट सित्तमों के हीय सरवार ने प्राप्त हैं परंतु नेपानी सिवधान के अनुसार यह रोनो प्रतियों नेपात नरेस म अधिष्ठित हैं। उसकी चांकिया को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह बीमर सबिपान क प्रव के जमन समाद स कम शक्तिवाली नहीं है। प्रतिनिधि सस्पाएँ उसकी धाया सात्र हैं। सन्दन्तानीन सक्तिमें उस तानासाह बना देती हैं। मित्रमण्डल ही नहीं यायपासिका भी उसकी छाया मात्र है। सभी महत्वपूण निषय उसकी सहसति सं सिय जात है। " राजसभा

1 1

नेपाल व धतमान सविधान की इस सस्या—राजसना (Ray Sabha) — की वितना हट ब्रिटेन की प्रीको परिषद (Privy Council) स की या सकता है। राजसमा मिन-परिवर की मीति कामकारिकी संस्था है। यह विचार विमा हरत वाली एक स्वायी सस्या है। इतम दा जनार न वस्त्य होन हूं—(1) वस्त, एव (2) मनोनीत । मूल्य वायापाद राष्ट्रीय वा नगर व अवस्य हुए हू । उपन्यास्त्रीत का निवास १२) भागाव १ प्रत्य वावावाचं वाद्भाव प्रशासन का काव्यन, भा व भागाव स्थापन वाद्यात स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्था

महा यायवादी आदि राजसमा क पदन सदस्य हात है। 🗆 राज्य 🖛 👻 यास्त्र क्षेत्रा मं स्थातिनामा एवं विधिष्ट सेवाजा के निए प्रसाद ब्याक्टर के संबंधि 🗆 🖚 समा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। समाट हारा का गण्य की गुन्त कर जाती है। राजसमा के अधिवसन सम्राट द्वारा बारून किस 🗷 📑 📑 📑 रह उपस्थित होता है तो स्वय राजसमा की अध्यक्षता काटा है। कार का कर्मा की म युवराज एवं उसके (युवराज) 18 वर्ष संक्रम जानु का जान जा जानाज का उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है । मन्नाट क निवन व व्यवस्था न या चार मित्रया सहित राजसभा के एक-कायह बान्य ब ह्या गॉक्टन्य को आपन करन के लिए यदि यह वह कर प्रापना का बाना है कि नाम का नामी के नाम कि रूप से अक्षास्य होने के बारण सभा का अधिकान बुगन में अन्याद है जा राजाता है सचिव को अधिवशन आहत करन का अधिका उन्हें र जाउनका को कम्यूनि 🚓 लिए एक तिहाई सदस्या की उपन्यिति जन्त्रक ना ह नाज्यक का 🛊 न्यादः समिति होती है। इसम 7 स 15 दर नका हा निपुत्र नक्ष्य गार है। स्वयन का कायकाल तीन वय हाता है । उपन्या का सम्प्राप्त काल पार्टिंग प्रत्या प्रमुखंबर्ग म उसके द्वारा मनानीत दूसरा व्यक्ति होता है जा नामाँह है। १९४१ सम्राह द्वारा राजसमा में विचासर्थ प्रम्तुत हिर ब्रास्कर है। जर समार राजस्का द सभा कार्यो को सम्मादित करती है। कहन दिन्न गर गर द्वार प्रान्तिक स ना। प्राप्त है (1) सम्राटका मृतु राज्य जाह हा जिल्लाक चारन पर र, जार राम हा घोषणा ।

602 | आधुनिक शासनत त्र

संविधान म राजसमा को स्थापना की गयी है। स्मरणीय है कि राजसमा दितीय के रूप म काय नहीं करती है। यह विद्युद्ध परामग्रदायी निकाम है जिससे स हारा आवस्यकतानुसार अपने कार्यों के सम्पादन के सम्य म परामस हि जाता है। मित्र परिषद

संविधान द्वारा सम्राट की अध्यक्षता म एक मिन परिपद की व्यवस्था की गयी है जिसम समार हारा निमुक्त म नी होते हैं। म नीमण समार को समित्व समारत म सहयोग एव सहायता देते हैं। संत्राट हारा मिन-परिपद का निर्माण किया जाता है। सम्राट को मिन्नयों को निमुक्ति सम्ब भी अतियनित अधिकार प्राच के सिक्त प्रथम तक्यानिक संशोधन (1967 ई) के अनुसार यदि सम्राट वाहे तो प्रधानम भी एव चप प्रधानम त्री की निवृक्ति के स देश में बहु राष्ट्रीय प्रचारत से परानश कर सकता है। प्रथम संबोधन के वृत्र प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री को मित-परिपद का अध्यक्ष एव उपाध्यक्ष कहा जाता था। सम्राट मित्र परिपद का अध्यक्ष होता है। वह अपनी अनुपत्त्विति म किसी अय सदस्य को मित्र-गरियद के अधिवेशना की अध्यक्षता के लिए नियुक्त कर सकता है।

प्रथम संघोधन (1967 ई) के अंतगत मि न-गरिपद का संगठन समाट की बजाय प्रधानमंत्री की अधीनता य होता है। कमी-कमी तो सवाट ने स्वय प्रधानमंत्री का पद भी महण किया है। उदाहरनाथ, 1960 ई म सम्राट स्वय तीन वय तक प्रधानमनी बने रहे थे। अपल 1970 ई म मित्रमण्डल के त्यागपन पर सम्राट मे अपनी अध्यक्षता म मिनमण्डल का गठन किया था। अत सम्राट प्रधानमंत्री के वाधित्व एव पद महण करता है। यह स्थिति समस्त ससदीय देशा में प्रचलित व्यवस्था के विपरीत है। नेपाली प्रधानमंत्री का कायकाल 5 वप है। वह इस अवधि क पूर्व भी पदत्याम कर सकता है। उसके पहत्याम के साथ सम्मूण मिन-परिपद की पहत्याम करना पडता है।

में त्र-परिपद को सदस्य सरया सविधान हारा निश्चित नहीं है। मीत्र परि-पद म दो मकार के मं नी होते हैं—(1) सम्राट के मं त्री, तथा (2) सहायक मंत्री। तमी मि त्रमण राष्ट्रीय पंचायत के सदस्य होते हैं। यदि कोई मंत्री अपनी निपुक्ति का समय राष्ट्रीय प्वायत का संस्था नहीं है तो 6 माह को अविध म उस राष्ट्रीय वनायत का सदस्य ही बाना चाहिए। सभी मनी सम्राट के प्रति उत्तरदायी हीत हु वे इगलप्रह एव मारत बादि संसदीय देशों की गीति राष्ट्रीय पंचायत के प्रति 54 S Narayan India & Nepal 1971, p 83

⁵⁵ Article 25 (1)

⁵⁶ सहायक म त्री सम्राट बारा सम्राट क यत्त्रिया की सहायवार्य निमुक्त किय

उत्तरदायी नहीं होते हैं। मंत्रीगण त्यागपत दे सकते हैं। वे राष्ट्रीय पचायत की सद स्वता के समाप्त होने या पदच्युत हो जाने पर अपने पद से हट जाते हैं। इसके अति-रिक्त राष्ट्रीय पचायत के कुल सदस्या के बहुमत द्वारा पदच्युत किये जाने की याग करने और सम्राट द्वारा उसके स्वीकृत होने पर मित्रयों को पदत्याग करना पडता है।

मिन परिषद के काय — सिन-परिषद देश की कायपालिका सक्तियों का उपभीग करता है। सिवान ये इसके कार्यों का कोई उत्सेख नहीं है। सामा यत मिन्न परिषद सासन की नीति निर्धारित करती है, राष्ट्रीय पचायत के विधायी कायक्रम की निविचत करती है, उष्ट्रीय पचायत के विधायी कायक्रम की निविचत करती है एव उसके द्वारा विधेयक करतावित किये जाते है। वापिक आय व्यय प्रपन एव आर्थिक नीतिया भी निर्धारित करती है। विभागीय अधिकारिया एव उनके कार्या के मध्य समयव स्थापित करती है। वह देश से खाति एव व्यवस्था के लिए उत्तरवायी है। वेश के प्रशासन का भार उसी पर होता है।

मुरुवाकत—नेपाली मि न परिषद म ससदीय व्यवस्था की मुख्य अवशारणा मि निमण्डल सम्राट के प्रति जत्तरदायित्व का अभाव है । नेपाली मि निमण्डल सम्राट के प्रति जत्तरदायी होता है, न कि राष्ट्रीय प्रचायत के प्रति । नेपाली प्रधानमानी की रिपित ब्रिटिश प्रधानमानी की मौति के प्रीय नहीं होती है, वह मि नमण्डल का प्रमुख होता है पर तुदेश का वास्तविक कायपालिका प्रमुख स्थाट ही होता है। वह सुनधार होता है। सम्राट स्थय प्रधानमानी बन सकता है। यह व्यवस्था ससदीय व्यवस्था के स्वीकृत सिद्धान के विपरीत है। सम्राट हो पर निमण्डल का नियुक्त करता है। नपाल के मनीगण सम्राट के सेवक होते है।

पाक कायपालिका

पानिस्तान के जाम (1947 ई) से 1956 ई म पानिस्तान के इस्लामी गणराज्य के सिवधान के उदधाटन तक, मारत वासन अधिनयम 1935 ई के अनुसार देश का शासन चलता रहा था। काँग्रीम कायपालिका म दो जग थे—
यननर जनरल एव मित्रमण्डल। गवनर जनरल राज्याच्यक्ष था। थी मोहम्मद अली
जिजा जब तक गवनर जनरल रहे वे ही सत्ता के केंद्र थे। उनकी मृत्यु (11 सित
म्बर, 1948 ई) के पश्चात सत्ता का के द्वीकरण प्रधानमंत्री के पर मे होता चला
गया। थी लियाकत अली खा पाकिस्तान में प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे देश म अरतधिक प्रमावशाली थे। थी जिजा की मृत्यु के पश्चात थे सत्ता के कंद्र वन गय थे।
उस समय पाकिस्तान म सवदीय कायपालिका थी। बिजमण्डल विधानमण्डल के प्रति
उत्तरदायी होता था, सामृत्विक उत्तरदायिव का सित्रमण्डल का त्रता होता था। थी माहम्मद अली जिना की मृत्यु के पश्चात स्वाचा
निजामुद्दीन गवनर जनरल वर्ग और विधाकत अशी की हत्या के पश्चात विधान

⁶⁰⁴ | आधुनिक जासात त्र

17 अपन 1953 इ को जिलामुटीन को परच्युत कर दिया गया और था महास्वरक्ष बोगरा को जनव स्थान पर श्रमनम श्री नियुक्त किया गया। ॥ अगस्त 1955 है जनक को बोगरा ने वागपत्र र अधानम जा । नपुरा । १४ वर्गाता, १८८८ । १४ वर्गाता । वर्णाता । वर्गाता । अनी न परवान मंभी प्रधानमं भी समवार से। गमनर जनस्त की सिक्त में अस्य विद्धि होन त्रमो थी। त्रीतन मुस्तिम त्रीम म मुद्धव दी एव 1954 हूं क पूर्व बनात क निवाचना म तीम की पराजय ने दश म राजनीतिक अस्पिरता का जम हिंगा 23 माच 1956 ई का पाक्सितान के इस्तामी गणराज्य के सविधान की लागू किया गवा जो 8 अक्टूबर 1958 इ. को समाप्त हो गया।

"म मिन्यान के अंतगत गवनर जनरत का स्थान निर्वाचित राष्ट्रपति ने त लिया। विक्रित गामन का स्वास्त्र प्रवस्ति का स्थान । विक्रित गामन का स्वास्त्र मतदीय ही क्वा रहा। राष्ट्रपति वह क तिए वी बहिताने निन्तिन की गयो थी उनक अनुसार प्रत्याशी का मुससमान एक कम स कम 40 वेद की आयु को होना आवस्तक या। जैसका कावकात १४ विषय में भी ही बीर में अधिक व्याप्तक या। जैसका कावकात 5 वद था। कोई भी दी बार ते अधिक राष्ट्रपति गही हो सचता था। उसका काववाल ३ वप था। भार भागा भागा स्वाधिकोक काक व्यक्ति हो सचता था। राष्ट्रीय समा अपने वो तिहाई बहुमत से महामियोग होंगे गाटुपति को पदच्चेत कर सकती थी। राष्ट्रपति के महाक होने या उसके पढ़ के रिक्त होने वर रिष्ट्रीय समा का अध्यक्ष उसका स्थान ग्रहण कर

4

राष्ट्रपति को मित्रमण्डल कं परामर्धानुसार काम करना आवस्पक था। प्रधानमञ्ज्ञो मिन्नमण्डल का वस्त्रभावतः, प्रधानमञ्ज्ञो मिन्नमण्डल का नता होता था। राष्ट्रीय समा स बहुमत दल का नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त किया जाता हाता था। पान्ना प्रभाव प्रभाव किया जाता था। मित्रमण्डल सामूहिक रूप से राष्ट्रीय समा के प्रति उत्तरदायी होता था।

अवटूनर 1958 इ. की सनिक काति के फसत्वरूप मेचर जनरत अपूर सौ क हाथा म सत्ता आ गयी थी। ससदीय प्रणाली का अंत कर दिया गया था एव अनुव होरा राष्ट्रपति मित्रमण्डल का निर्माण किया गया जिसम तीन सनिक व बाठ असनिक अधिकारी दें। योना प्राप्ता के राज्यपाल इस मित्रमण्डल क एटेन सहस्य थ । असैनिक अधिकारिया की सरया बाद म बढाकर 10 कर दी गयी थी । 1962 ई के संविधान क क्रिया कित होने तक वह मिनमण्डल राष्ट्रपति की अधीनता म काय करता रहा। 1962 ई के सविधान के अधीन कायवातिका

इस सिवधान द्वारा पाकिस्तान भे गणराज्य की स्यापना की गयी। काव पातिका को त्वरप कुछ अध्यक्षात्मक सा था। संसदीय यवस्या का परित्याम कर त्या होता एवं पाविस्तान के राष्ट्रपति को निर्वाचन मण्डल होरी चुने जाने की व्यवस्था की गयी थी। राष्ट्रपति हारा ही प्रधानम त्री नियुक्त किया जाता था एव उसी के प्रति वह उत्तरतायों भी होता था। वं बमेरिकों में वियो की भीति राष्ट्रपति

के सेवक थे। मानीगण राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। मानिमण्डल की स्थिति बहुत कुछ क्रिटिश मारत के यवर्गर जनरस की कायकारिणी परिषद के समान थी। पाक राष्ट्रपति के पद से अक्रीरिकी एव फासीसी राष्ट्रपतियो एव ब्रिटिशकांसीन मारतीय गवनर जनरल की शक्तियों और स्थितियों का समायय था। राष्ट्रपति राज्य सथा शासन दोनों का प्रधान था।

निर्वाचन —पाक राष्ट्रपति को एक निर्वाचक मण्डल द्वारा निर्वाचित किया जाता था। दोनो पाक प्रात्तो को समान जनसख्या वाले समान निर्वाचक क्षेत्रीय इका-इयो मं विवाजित किया गया था। प्रत्येक प्रात्त को कम से कम 40 हजार निर्वाचक क्षेत्री मं विवाजित किया गया था। प्रत्येक प्रात्त को कम से कम 40 हजार निर्वाचक क्षेत्री को समान सत्या आवश्यक नहीं थी। प्रत्येक दोत्र की एक निर्वाचक सूची होती थी। प्रत्येक 21 वर्षीय पाक नावी। प्रत्येक दोत्र की एक निर्वाचक सूची होती थी। प्रत्येक 21 वर्षीय पाक नावी। किसी किसी निर्वाचन क्षेत्र को निर्वाचन के मानिस्क सूची मे दक कराने वा अधिकारी होता था। निर्वाचक सूची के सदस्य अपने मे से ही एक सदस्य को वृत्रते थे। निर्वाचित सदस्य को 25 वप से कम आयु का नहीं होना चाहिए था।

दोनो प्राप्ता के निवाचन क्षेत्रो के निर्वाचक सामूहिक कप में राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल क सदस्य कहें जाते थे। इह ही राष्ट्रपति को निर्वाचित करने का अधिकार प्राप्त था। अत पाक राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष कए म चुना जाता था। राष्ट्रपति के कायकाल की समाप्ति के 120 दिन पूज उसको निर्वाचित करना आवस्यक था। यदि राष्ट्रीय समा मग हो जाती थी तो 120 दिन में राष्ट्रपति का निर्वाचन होना आवस्यक था और यदि राष्ट्रपति कपने कायकाल की समाप्ति के पूज ही पदमुक्त होना चाहता था तो ऐसी अवस्था में 90 दिन में ही निर्वाचन का विधान था।

अहताएँ—राप्ट्यति पद की निम्नलिखित अहताएँ निर्धारित की गयी थी

- (1) राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को मूसलमान होना चाहिए।
- (2) उसकी आयु 35 वप या उससे अधिक हानी चाहिए।
- (3) राष्ट्रीय समा की सदस्यता सम्बन्धी सभी योग्यताओ को उसे पूण करना चाहिए।
- (4) राष्ट्रपति पद के लिए अधिक से अधिक तीन प्रत्याची हो सक्ते थे। यदि प्रत्याचियों की सरसा 3 से अधिक होती थी तो निवाचन आयुक्त राष्ट्रीय समा के अध्यक्ष को तत्सम्बंधी भुनना देता था और तुरत ही राष्ट्रीय समा एव प्रातीय विधानमण्डलो ना संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जाता था और उसम पुष्त मतदान हारा तीन प्रत्यादिया का चयन चिया जाता था। श्रेष सभी प्रत्यादिया को राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु अयोग्य ठहरा दिया जाता था।
- (5) जाठ वर्षों से अधिक समय तक राष्ट्रपति पद पर निरत्तर पदासीन रहते वाला व्यक्ति पुन उस पद का प्रत्यानी नहीं हो सकता था। यदि कोई राष्ट्रपति

दुवाग चुनाव लहता था तो ऐसी अवस्था म यह तभी प्रत्याची हो सकता था वात राष्ट्रीय सभा एव प्रातीय समावों के संयुक्त वाधिवेदान म उस दुवारा निवास के मान लेन की अनुमति दो गयी हो। राष्ट्रपति का कामकाल 5 वप निवित्त कि गया था। पद पाल करन वह अपन पद से पृषक हो सकता था। राष्ट्रपति का अपना राजापण राष्ट्रपति का अपना राजापण राष्ट्रपति का अपना राजापण राष्ट्रपति का अपना राजापण राष्ट्रपति मान के अपना को प्रतिवत्त का गा। राष्ट्रपति को स्वान या। राष्ट्रपति को स्वानका या। राष्ट्रपति में स्वान या। अस्तानका या। अस्तानका या। स्वान स्वान प्राप्ट्रपति मान के एक विहां सहस्यो होरा सर्विधान के अतिष्ठमण एव दुराचार के आरोशे पर महामियोग का अस्तान उपस्थित किया जा सकता था। महामियोग के प्रतान पर विचार हेतु अपस हारा राष्ट्रपति समा का अधिवेदान बुलाया जाता था। यदि महामियोग अस्तान को तीन चीयाई वहुमत से राष्ट्रीय समा क्यो अपन बोता या। यहि महामियोग अस्तान की तीन चीयाई वहुमत से राष्ट्रीय समा क्या अधिवेदान बुलाया जाता था। यहि महामियोग अस्तान की तिन चीयाई वहुमत से राष्ट्रीय समा क्या अस्तान को विक्यूत

शक्तियों एवं अधिकार--राष्ट्रपति की निम्न चित्तयों थी

(1) कांधपालिका प्रविद्यां के प्राप्त की प्रमुख कायपालिका था एव स्वय या अपने अधीनस्य अधिकारियों के प्राप्तम से इन सिक्यों का प्रयोग करता था। वह पार तेनाका का सर्वोच्च सेनाधित था तथा सैनिक अधिकारियों को मेना ना कमीयन अदान करता था। वह मित्र परिवद का निराण करता था तथा आतीय राज्यपाला की निमुक्त करता था। वह मित्र परिवद का निराण करता था तथा आतीय राज्यपाला की निमुक्त करता था। वे सभी उसक निर्वेचन में काय करते थे। मित्रपो या गवनरों को करवा सम्ब धी गम्मीर दुराचार के आधार पर राष्ट्रपति परक्युत कर मकता था। उस अप उच्च पदाधिकारियों जस कि महातेखा परीक्षक, महायायवायी एवं समदीम सिच्या की निमुक्त करने का भी अधिकार प्राप्त था। वह इन अधिकारियों की वित्ता कारण बताय हुए एक्च्युत कर सकता था। राष्ट्रपति की सहमति के कमान म आतीय राज्यपाला को पदच्युत नहीं किया वा मकता था। वह साक्षन करारों का विमाजन तथा नकीन विमायों का निर्माण करता था।

(2) विधानी शक्तिया—राष्ट्रीय समा हारा पारित विधेवका का राष्ट्रपति स्वान करता था। वह विधेवको को रोक सकता था वा उद्द पुन विवार केतु मदन करता था। वह विधेवको को रोक सकता था वा उद्द पुन विवार केतु मदन को वापस नेक सकता था। यदि राष्ट्रपति 30 विन क अदर उपरोक्त करमा ने से काई कदम उठाने में असमय रहता था तो विधेवक पारित पाना वाता था राष्ट्रीय समा को राष्ट्रपति वो गर्देश प्रेकने का अधिकार था वह तस सम्बोधित कर सकता था एव किमो समय भी राष्ट्रीय समा को विध्येदत कर सकता था। यित्र परितय या पहा याकारी को राष्ट्रीय समा और उनकी स्वित्रियों में विवार अस्ति कर राष्ट्रपति सम्बान या पहा याकारी को राष्ट्रीय समा और उनकी स्वित्रियों में विवार अस्ति कर राष्ट्रपति की पूष्ट-स्वीकृति वे विवार कर सकते थे। निवारक निरोध सम्बाची विधेवक राष्ट्रपति की पूष्ट-स्वीकृति वे ही सदन म अस्तुत किये जा सकते थे। निवारक निरोध सम्बाची विधेवक राष्ट्रपति वे एवंदीन समा

म मतभेद की अवस्था म विवादास्पद विषय पर जनमत सम्रह लिया जाता था। जन-मत सग्रह मे केवल राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल के सदस्य ही माग से सकते थे। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार या लेकिन उन्हें राष्ट्रीय समा के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक होता था।

(3) चायिक शक्तियाँ-राप्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त थी। वह किसी भी यायालय द्वारा दण्डित अपराधी को क्षमा प्रदान कर सकता या या उसे दिये

गये दण्ड को निलम्बित अथवा स्थगित कर सक्ता था।

(4) सकटकालीन शक्तिया-पाक राष्ट्रपति को युद्ध अथवा बाह्य आनमण या उसकी सम्भावना एवं जा तरिक सुरक्षा तथा आधिक जीवन को सकट उत्पन होने या प्राप्तीय शासन के ठीक प्रकार से न अलन की स्थिति म सकटकाल की घोषणा करने का जिंबकार प्राप्त था। पर तु ऐसी सभी घोषणाओं का बीव्रातिशीव्र राष्ट्रीय समा के समक्ष उपस्थित किया जाना आवश्यक होता या बद्यपि उसके द्वारा अनुमोदन अनिवाय नहीं था । मकटकाल को राष्ट्रपति अय घोषणा से समाप्त कर सकता था। सकटकाल मे उसे राप्टीय समा के सनकाल मे ही जध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त या । ऐसे आदेश सकटकाल पयात ही प्रमावी होते थ ।

राष्ट्रपति की मित्र परिषद

राप्ट्रपति ही अपने मित्रयो की नियुक्ति करता था। मित्रयो के लिए राप्ट्रीय समा का सहस्य हाना आवस्यन नहीं था। पर तु उ ह स्विटजरलण्ड नी सधीय परिपद के सदस्यों की नाति राष्ट्रीय समा म भाग लेने का अधिकार प्राप्त था यद्यपि वे समा मे मतदान नहीं कर सक्ते थे। प्रत्यक विमाग का एक ससदीय सचिव होता था जो राष्ट्रीय समा के अधिवेशना में अनिवायत मांग लेता था और उसमें मतदान भी करता था। मानी राष्ट्रपति के प्रसाद-पथन्त ही पदाकृढ रहते थे। उनके परामधा हो स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति का अधिकार था। स्पष्ट है, पाक मित्रमण्डल के सदस्य ससदीय मित्रमण्डलीय व्यवस्था एव अमेरिकी मित्रयो स मिन थे। संसदीय मित्रमण्डलो से जनका कोई साम्य नहीं था। पाक मित्रमण्डल ब्रिटिश मित्र मण्डल की माँति राष्ट्रीय समा के प्रति उत्तरदायी नही होता था। राप्टपति की स्थिति

पाक राष्ट्रपति ससदीय देशा के सवधानिक अध्यक्षो की स्थिति नही रखता था। उस व्यापक शक्तियाँ प्राप्त थी। प्रतिरक्षा एव वित्त पर राष्ट्रीय समा को नोई अधिकार नहीं थे। वे राष्ट्रपति के सीचे नियत्रण मंधे। राष्ट्रपति अयुव न स्वय अपने ही प्रथम मि त्रमण्डल म सुरक्षा विभाग सम्माला था। राष्ट्रपति को पदच्युत करने नी व्यवस्या अत्यधिक जटिल एव कठोर थी। बत उसकी सफलता की नोई आशा नहीं थी। जनरत अयूब 1962 इ कं सविधान के अतगत जनवरी 1965 ई म प्रयम राप्टपति निर्वाचित हुए थे।

21

भारतीय संसदीय कार्यपालिका [INDIAN PARLIAMENTARY EXECUTIVE]

भारत म संसदीय कायपालिका स्थापित की गयी है। ग्रेट ब्रिटेन के सविधान का नारतीय सविधान पर व्यापक प्रमाव है तथा मास्त म मी ब्रिटिश संवदीय प्रवासी का ही अनुष्यमन किया गया है। राष्ट्रपति नाममात्र की कायपालिका है, मिन-मण्डल वास्तिविक कायपालिका है। प्रधानम त्री मित्रमण्डल का नेता होता है अत वह के द्वीय कायपालिका शक्ति का चालक चक्र है। राज्यों में राज्यपाल नाममात्र की कायपालिका एवं राज्य का मी निमण्डल वास्तविक कायपालिका होते हैं।

सिवधान के अनुसार तथ की कायपालिका श्रक्ति राष्ट्रपति य निहित है। व संशहन सेनाजो का सर्वोच्च सेनापति है। ये सेकिन राष्ट्रपति द्वारा कायपालिका शक्ति का प्रयोग सिवधान के अनुसार किया जाता है। सिवधान में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि एक मित्र परिपद होगी जो राष्ट्रपति को उसक कार्यों म सहायता एव परामस प्रदान करेगी तथा प्रधानम त्री मि त्र परिपद का अध्यक्ष होगा। अस अनु-ब्छेदा के सदम म इस अनुब्छेद का अध्ययन करने पर राष्ट्रपति की बक्ति एवं स्थिति स्पट्ट हो जाती है। मिनमण्डल राज्यात के प्रति उत्तरतायी नहीं है अपितु ससद के निम्न सदम-को प्रति सामूहिक रूप हे जसरवायी होता है। यिन परिपद ने निषम की सुनना राष्ट्रपति को प्रधानम त्री द्वारा दिये जाने का प्रावमान हैं। विविधान के अनुसार यदि राष्ट्रपति का अधानम ना हारा १९५ वर्षा है। विविधान के अनुसार यदि राष्ट्रपति किसी ऐसे विषय सम्बंधी प्रस्तान को मन्त्रि

अनुस्दान 74 (1)

अनुन्धेद 75 (3) अनुब्धे > 78 (अ)

परिषद के विचाराथ रखवाना चाहता है जिस पर नेवल किसी मानी न ही निषय लिया है परन्तु मनित्र परिषद न उस पर विचार नहीं किया है, तो उक्त प्रस्ताय को मनित्र परिषद के समक्ष रखना प्रधानमानी ना कतन्य होगा।

इन उपवास से यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति मिनमण्डल के परामश को मानन क लिए वास्प है। मिनमण्डल उसके प्रति उत्तरदायो नही है। कायपालिका के सभी दामित राष्ट्रपति के नाम पर मिनमण्डल द्वारा ही सम्पादित किये जाने का विधान है [अनुच्छेद 77 [1]। सविधान में ऐसी कोई परा नही है जो राष्ट्रपति को शासन के कार्यों के लिए उत्तरदायी टहराती हो। यही मही, राष्ट्रपति के नाम पर किये जाने याले समस्त कार्यों के लिए के द्रीय मिनमण्डल उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन

मारतीय राष्ट्रपति का कायकाल पद प्रहुण की तिथि से पाच वय है। वह पुत निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए मत्याची को मारत का नागरिक हाना चाहिए। उसकी आयु मी 35 वप से अधिक होनी चाहिए और उसमे ससद क निम्म सदन (लोकसमा) के लिए निर्वाचित होने की योग्यताएँ होनी चाहिए। शासकीय अधिकारियो को राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता। राष्ट्रपति ससद या किसी राज्य विधानमण्डल का सदस्य नहीं हो सकता और न मारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाम का कोई पद ही प्रहुण कर सकता है। उसका निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एव एकल सकमणीय मत के आधार पर एक निर्वाचक मण्डल द्वारा होता है जिसमे ससद के दोनो सदना तथा राज्य विधान-परिषदा के निर्वाचन पाया है जिस समस्त राज्य के मती एव सस्त्रण सथ के मतो म समानता स्थापित की गया है जिस समस्त राज्या के मती एव सस्त्रण सथ के मतो म समानता स्थापित की गया है वस समस्त राज्या के मती एव सस्त्रण सथ के मतो म समानता स्थापित की गया है। इस उद्देश्य हुतु राष्ट्रपति के निर्वाचन ये प्राप्त मता का मूल्याकन करने के लिए एक विधि का उत्सेख किया गया है।

राज्य विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य उस राज्य की जनसङ्ग्रा म निर्वाधित सदस्यों की सर्या का भाग देने पर प्राप्त सजनकल मधुन 1000 का भाग

देने पर प्राप्त मतो के वरावर होता है, अर्थात राज्य की जनसंख्या — 1000।

ससद के एक निर्वाचित सदस्य के मत का मुख्य राज्यां के कुल निर्वाचित सदस्या के मता में दोना सदनों के निर्वाचित सदस्यों का भाग देने पर जो भजनफल आता है उसक

⁶ अनुच्छेद 78 (व) ।

⁷ अनुच्छेद 54

৪ **এবু**ভটুর 55

⁹ अनुच्छेद 55 (1) एव (2)

बरावर होता है। मई 1952 ई म प्रथम राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय निराबन मण्डल के 4057 सदस्यों में से 3486 ने मतवान में नाम लिया था। 539 मध्य सदस्यों एवं 2357 राज्य विधानमण्डलों के सदस्या ने डॉ राज्य प्रधान, विजयी प्रत्याधी, को मत दिये थे।

राष्ट्रपति की निर्वाचन-पद्धति को समानुपातिक पद्धति की सज्ञा दी जाती है, सेविन यह गरत है। वेवल एक प्रतिनिधि का चुनते समय समानुपातिक पदिति नी प्रयोग सम्मव हो नही है। वस्तुत यह वैकल्पिक मत प्रणाली (Alternative Vote System) है। लेकिन डॉ मीमराव अम्बेडकर ने सविधान समा म राध्यपति की निर्वा चन पदिति के लिए 'समानुपातिक प्रतिनिधित्व' शब्द के प्रयोग की अवित मानते हुए यह मत व्यक्त किया या कि इस पढ़ित के अधीन अल्पसध्यकों को भी राज्य के अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रमावित करने के उचित अवसर प्राप्त होंगे। राय्ट्यति की केवल बहमत मे ही नहीं चुना जाना चाहिए। बत इस उद्देश की प्राप्ति समानुपातिक प्रणाली द्वारा ही सम्भव है ।10 उनके इस मत की सविधान समा मे ही आलोचना हुई थी । 1952 ई में भारतीय समद ने राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन मध्य थी विधि का निर्माण किया था। इसके अनुसार विजयी प्रत्याशी क लिए फोटा के बराबर मत प्राप्त करना आवश्यक है। कोटा का निर्धारण कुल प्राप्त मही मता म हो का भाग दने पर प्राप्त भाज्यफल में ! जोड देन स होता है । प्रयम बार म ही कोटा के बराबर मत प्राप्त करने पर प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया जाता है अन्यया इसरी पस दगी ने आधार पर मत गिने जाते हैं और इस बार मतो की गणना करन पर कोटा के बराबर मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी की विजयी घोषित किया जाता है। श्री वी वी गिरि प्रथम गणना स विजयी न होकर दूसरी गणना म निवाचित हुए थे। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी "ते समदीय विधि द्वारा कही की गयी है। अब राष्ट्रपति का नाम ससद एव विधानमण्डल के कम मे कम 20 सदस्यो द्वारा प्रस्तानित किया जाना चाहिए। मारतीय सर्वोच्च यायालय के अनुसार राज्यपति के निर्वाचन के समय यदि कोई राज्य विधानसमा सन है तो इससे राष्ट्रपति के निर्वाचन पर कोई विषरीत प्रसाव नहीं पढता न्यांकि ऐसी दशा म निर्वाचन प्रक्रिया में केवल एक स्थान रिक्त होता है।

राज्यपति त्यागपत्र देकर अपने पद स पृथक हो सकता है। उसे महामियोग द्वारा दुराचार के लिए भी पदच्युत किया जा सकता है। महामियोग के नोटिल के 14 दिन पदचात हो उस पर लोकसभा या राज्यमा विचार कर सकती है। इस महामियोग पत्र पर महामियोग प्रस्तुत करने वाले सदन के पर निहाइ सदस्य के हस्तान्यरा अपेशित हैं। उसे अपने बचाव म सदन में उपस्थित होंगे का अधिसार प्राप्त है। ससद के एक सदन म आरोप प्रस्तुत करने और दूसरे सदन द्वारा आरोप की जांच किये जाने को व्यवस्था है। यदि दोना सदन—सोक्समा तथा राज्यसमा—प्रस्ताव को अपने कुल सदस्या के दो तिहाई बहुमत से पारित कर देते है तो राष्ट्रपति को अपने पद से पृथक होना पडता है।

राष्ट्रपति की शवितयाँ

इ' ह निम्न श्रेणिया म वर्गीकृत कर सकते हैं

कायपालक शवितवी—राष्ट्रपति देश की मुख्य कायपालिका है, सदाक्त सेनाओं का अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री के परामक्ष पर मित्रयों की नियुक्त करता है, अटोनीं जनरल उसी वें द्वारा नियुक्त किया जाता है एवं उसी के प्रसाद पय त पदाक्द रहता है। वह मित्रमण्डल के सदस्यों को गोपनीयता की शप्य दिलाता है और मारत सरकार के सभी निजय उसी के नाम पर निये जाते हैं। उसे शासन सचालन हेसु आवश्यक नियम एवं मित्रमण्डल में काय विमाजन सम्बंधी नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है।

प्रधानम श्री का यह कर्तव्य है कि वह सित्रमण्डल के सभी निणयों की राद्रपति को सूचना देता रहे। वह राज्यपाला, सर्वाच्च यायालय एव उच्च पायालयों के
पायाधीकों, वित्त-आयोग के सदस्यों, सधीय लोक सेवा आयोग के अव्यक्त एव सदस्यों
परिपाणित जाति के विशेषाधिकारी एव परिपाणित जाति आयोग को नियुक्त करता है।
कुछ विशेष परिस्थितिया में वह सर्वोच्च पायालय के मुख्य पायाधीश एव वर्ष यायाधीशों एव उच्च पायालय के पायाधीशों को पद से पृथक भी कर सकता है। सर्वाच्च
पायालय द्वारा अपन काथ सम्मादन के लिए निमित नियमा को वह मा यता प्रदान
करता है। राज्याध्यक्ष के रूप भ वह विदेशी राजदूता का स्वागत करता है।

कुछ विचारका के अनुसार राष्ट्रपति को युढ एव साित तथा सिंधयां करते के अधिकार भी प्राप्त हैं नयािक ये काय कायपालक शक्ति के ही अस हैं। पर तु इसके विपरीत यह तक दिया जाता है कि यह शक्तिया ससद को प्राप्त हैं। सविभान ने स्थाट इप मं यह शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान नहीं को है। इनका उल्लेख केवल संशोध सूची म है और ससद को सध सूची पर विधि निर्माण वा अधिकार प्राप्त है, पर तु इसका यह वर्ष नहीं है कि वदेशिक सम्बच्धो, युढ, शांति एव सिंध का नाय ससद को ही सम्पादित करना चाहिए। कायपालिका ऐसी स्थित उत्पन्न कर सकती है कि सदी का स्वाप्त हो जाय ।

राष्ट्रपति को राज्य के सादम म निर्देशन, नियात्रण एव समात्रय की द्यक्तिया प्राप्त है। सपीय कायणातिका इन उद्देश्यों के लिए राज्या को आवश्यक निर्देश दे तकती है। राष्ट्रीय एव सनिक मार्गों ने निर्माण एव इनके निरीक्षण सम्बाधी कार्यों को सपीय सरकार राज्यों को शीरे जाने सम्बाधी तथा रेल माग की रक्षा के लिए राज्यों के जपने-अपने क्षेत्र में आवश्यक कदम उठाने के लिए आदेश दे सनती है। राष्ट्रपति राज्या व समाचम ह्यु एक अन्त राज्यीय-परिपर' नी स्वास्त गर सनता है। ने द्र प्रशासित अन्या का प्रशासन राष्ट्रपति का दायित होता है, वह प्रशासका द्वारा जनका प्रशासन बन्धता है।¹³ वह निसी राज्य क राज्यपत की समीपस्य नाद प्रशासित प्रदेश का प्रशासन निमुक्त कर सकता है।

विषामी सांवतवां — विधायी क्षेत्र म राष्ट्रपति को स्थापक राक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति ससद को आहूत, स्थमित एव विषाटित वर सरता है, परातु ससद के हो सांचा 6 माह स अधिक बरा अ तराल नहीं हाना चाहिए। वह दोना सदनों की सम्बाधित वर सकता है एव जह न दस नेज सफता है। नव निवांचन क पश्चात नवीन साह के प्रथम सब एवं प्रति वप के प्रथम सम्बाधित व वह नापण दता है एवं सहस्वात के साह को आहत करने के कारणों पर प्रशाब हाता है।

सासद द्वारा पारित समस्त विधेयका पर यह हस्साक्षर करता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों के अमाय मं कोई विधेयक विध्व नहीं वस सकता। वह विध्यक को स्वीद्य स्व सकता। वस्त विध्यक को स्वीद्य स्व सकता। वस्त विध्यक को स्वीद्य सकता है। यदि विधेयक को सदी सकता है। यदि विधेयक को सदीभान सहित या बिना संग्रीभान के पुन पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के निष्य उस अपनी स्वीकृति प्रदान करना अनिवाय होता है। यन विधेयक सस्त में विचाराय प्रस्तुन करने के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणित किये जाते हैं। किसी राज्य के क्षेत्रकत, सीमा एक नाम परिवतन से सम्बिधत विधेयक को राष्ट्रपति की विकारिय के बिना समझ प्र प्रस्तुन नहीं विचा जा सकता 1¹⁴ वह दोना सदना मा समुक्त अधिकवान बुला सकता है। यह अध्यति जारी कर सकता है। वह अध्यति जारी कर सकता में प्रस्ता समुक्त अधिकवान बुला सकता है। वह अध्यति जारी कर सकता में प्रस्ता समुक्त अधिकवान बुला सकता है। वह अध्यति जारी कर सकता मा प्रदेश का साम समुक्त अधिकवान बुला सकता है। वह अध्यति जारी कर सकता मा प्रदेश का साम समुक्त अधिकवान विशासन लागू विच आने के पश्चात उस पाज्य या प्रदेश का साम समुक्त ना सम्व स्व साम समुक्त ना स्व स्व स्व साम समुक्त स्व साम समुक्त साम समुक्त साम समुक्त अधिकवान सकता है। वह अध्यति साम समुक्त अधिकवान स्व सम्बन्ध स्व साम समुक्त साम सम्बन्ध सम्म सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध साम सम्बन्ध सम्बन्ध समा सम्बन्ध सम्बन्ध सम्म सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध समा सम्बन्ध सम्म सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्म सम्बन्ध सम

बिसीय प्रशितयां—यजट सहित ममस्न वित्त विधेयका का ससद म राष्ट्रपनि द्वारा प्रमाणित किये जाने क पश्चात ही प्रस्तुत विया जाता है। वित्त आयोग एव नेवा नित्त अक एव महानम्बा परीक्षक कं प्रतिवेदना को मविधान कं अनुसार ससद के समक्ष प्रस्तुत करना राष्ट्रपति का ही काय है। सचित निधि में सच्या राष्ट्रपति कं अधिकार सही किया जा सकता है। जाय-कर एव वाय करो से प्राप्त राजस्व में राज्यों के नाग को राष्ट्रपति हो निर्धारित करता है।

मायिक शक्तियाः—राष्ट्रपति का क्षमा प्रदान करने, दण्ड को कम करने या पूणरूपेण समाप्त करने का अधिकार होता है। सनिक यायालय द्वारा दिये पये मत्यु दण्ड को भी वह कम या ममाप्त कर सकता है। स्मरणीय है कि सचीय विधि

¹¹ अनु≈छेद 239

¹² अनुच्छद ३

¹³ अनुच्छेद 123

के उल्लपन हेतु प्राप्त दण्ड के सम्बाध म राष्ट्रपति को ही क्षमादान आदि का अधिकार प्राप्त है।

सकटकालीन शिवतमां 16—सिविधान में तीन प्रकार की आपातकालीन या सकट-कालीन स्थितिया का उल्लेख किया गया है—(1) युद्ध या आवरिक विद्रोह से उत्पन्न सकट¹⁵, (2) राज्य या राज्या में सबैधानिक सासनत न की असफलता वे कारण उत्पन्न सकट¹⁶, एवं (3) वित्तीय सकट। 17

युद्ध एव आ तरिक विद्रोह क कारण या उसकी सम्मावना स यदि देवा या उसके किसी माग को असुरक्षा उत्यन्न हो आय ता राष्ट्रपति समय्त मी कर काल को योपणा कर सकता है। ऐसी घोषणा को बाद म राष्ट्रपति समय्त मी कर सकता है। योपणा को सदाव के दोना सदना के समक्ष स्वीकृति हेतु रखना आवश्यक है। यदि सस्य के दोना सदना के हारा सकटकालीन घोषणा की प्रस्तावो हारा पुष्टि नहीं की जाती है तो वह दो माह के पश्चात स्वत ही निष्प्रमायी हो वाती है। लोकसमा के विष्टित होने क पश्चात यदि ऐसी घोषणा की जाती है या घोषणा के दो माह के मीतर कोकसमा विषटित हो जाती है तथा राज्यसमा सकटकालीन घोषणा सम्बच्धी प्रस्ताव पारित कर देती है तो नविनिमत लोकसमा के प्रथम अध्वेद्यक के प्रयम दिन के तीस दिन पश्चात घोषणा स्वत् ही निष्प्रमायी हो जाती है, यदि लोकसमा बारा इतके पुत्र घोषणा की पुष्टि सम्बच्धी कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया जाता। 19

इस पापणां के पलस्वरूप के द्र की कायपालिका श्रस्ति का क्षेत्र राज्यो तन विस्तृत हो जाता है एवं वह राज्या का उनकी कायपालिका श्राक्ति के प्रयोग सम्याधी निवेंश दे सकती है। इस प्रकार के द्रीय ससद ना सम सूची के श्रतिरिक्त अन्य विषया के सदम में विधि बनाने या कर लगाने या कर द्रीय अधिकारियों को इन अन्य विषयों में अधिनार देन की श्रिक्त प्रान्त हो जाती है। 19 268 स 279 तक के अनुच्छेद स्वार्ध ही निलन्तित हो जाते हैं या राष्ट्रपति के निवेंशानुसार क्रियावित होते हैं। 19 अक्रमण या आवित्व अधाति से राज्यों की रक्षा का द्राधिव के द्र पर होता है। 14 विधिन प्रकार के स्वतंत्रता सम्बंधी अधिकार (अनुच्छेद 19) सक्रट-काल प्र

¹⁴ माग 18

¹⁵ अनुच्छेद 352

¹⁶ अनुच्छेद 355

¹⁷ जनुष्छेद 360 18 अनुष्छेद 352

¹⁸ अनुच्छद ३५२ 19 अनुच्छेद ३५३

¹⁹ अनुन्छद 354 20 अनुन्छेद 354

²¹ अनुच्छेद 355

⁰¹⁴ | आधुनिन सासनते त्र

निलम्बित हो जात हैं तथा कायपालिना और व्यवस्थापिना द्वारा इनका अतिनमण निये जा। वर सर्वोच्च यायातय एव उच्च यायातय स इननी रहा। का कोइ अपिकार माप्त नहीं रह जाता है।

राज्यो में सवधानिक सासनतत्त्र की विकलता—इसके फलस्वरूप द्वितीय प्रकार की सक्टकालीन अवस्था उत्पन्न हो जाती है। राज्य के राज्यपाल स यह प्रति वंदन प्राप्त होने पर कि संविपान की घाराओं के अनुसार राज्य का सासन नहीं चल सकता, सम्ब पत राज्य म राष्ट्रपति धासन की घोषणा कर दी जाती है और राष्ट्र पति का सासन तामू हो जाता है तथा राज्यपात के कवन्य राष्ट्रपति वहन कर लवा हैं। राष्ट्रपति को यह योपणा करने का भी अधिकार है कि विधानमण्डल की शक्तियाँ संसद ने अधिनार के अनुसार प्रयुक्त नी नायंगी। राष्ट्रपति को इस प्रकार की चोवणा वर्ग प्रमायो करने के लिए आवस्यक बदम उठाने का अधिकार है परेली उच्च नागा। त्र सम्बन्धी सक्तियाँ राष्ट्रवति स्वय बहुन नहीं कर सक्ता है और न उच्च पाणालय पथ प्रस्थ था धारतथा राष्ट्रमाध रच्य यहार महा मर धा धा छ थार ग पण्य पाथापथ सम्बन्धी निसी सबद्यानिक प्रावदान की निर्ताम्बत ही कर सकता है। इस प्रकार की पीवणा को राष्ट्रपति किसी अन्य परिवर्ती घोवणा द्वारा समाप्त कर सकता है। यह भाषणा मारम्म म 6 माह के लिए की जाती है और 66 माह करके हते अधिकतम तीन वय भी अवधि के लिए बढाया जा सकता है।

राष्ट्रपति शासन-काल म राज्य विधानमण्डल की शक्तिया का प्रयोग ससद के आदेशानुसार किया वा सकता है। ससद इन सक्तियों को राष्ट्रपति को प्रदान कर सकती है या इन शक्तियों को वह जिसे चाहें प्रदत्त करने का अधिकार दे सनती है। वण्या ६ वा व्यापात्रा गा १९ १०० ११९ ववस १०५० गा व्यापमार व घरण ६। राष्ट्रपति लोकसमा के समावसान कास में सचित निधि में ते स्वयं के लिए घन स्वीकृत भर परणा हु १९ इ.स. १९८८ है। अपने का इस सकट काल में निवस्तित किया जा पुष्त के और यायालया को प्राप्त मौलिक अधिकारा के रक्षा सम्बंधी अधिकारा को भी निलम्बित किया जा सकता है।2

राज्य राज्य, जा उन्तर, ह . सनप्रयम 1951 ई में पंजाब में और उसके पश्चात अनेक राज्या में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कभी तक तीन बार लागू ही चुका है।

उण ६ । वित्तीय सकटकालीन घोषणा—यह विस्तास होने पर कि भारत या उसके किसी माग की वित्तीय सास को खतरा जलम हो गया है, रास्ट्रपति सकटकाल की किया भाग का (बचान वाल का बचन करते हैं। घोषणा कर सनता है। राष्ट्रपति की परिवर्ती घोषणा के बारा ऐसी सकटकालीन वायभा कर घरवा है। अञ्चलका का अभ्यास का अभ्यास का अस्ति विक्तीय घोषणा सम्बन्धी आदेख को संसद के दोनो 22 अनुच्छेद 357 23 अनुच्छेद 358

सदना ने समक्ष प्रस्तुत करना आवस्यव है। वित्तीय सवट-काल म ने द्र अपनी वाय-पातिका दाक्ति ने अन्तवत किसी भी राज्य का निर्धारित वित्तीय नियमा एव अय निर्देशा ने पातन हेतु आवस्यव निर्देश दे सत्ता है। सर्वोच्च न्यायात्मा के न्याया-पीशा सहित राज्य एव सपीय नमचारिया ने वेतन एव मत्ते कर करन सम्ब भी आदेश राष्ट्रपति द्वारा दिये जा सकत हैं। राज्य विधानमण्डला द्वारा पारित समस्त धन-विषयना ना राष्ट्रपति के विचारार्थ प्रस्तुत करने के आदेश भी दिव जा सकत है। राष्ट्रपति की स्थिति

भारतीय नवधानिक प्रणाली म राष्ट्रपति की स्थिति की लेकर सविधान के प्रारम्म स ही गम्भीर वियाद उठ खडा हुआ है। अधिवक्तागण (Lawyers) सवधानिक विधि भी सीमाओं वे परे देखने म विश्वास नहीं करते हैं और सर्विधान की मापा के भाधार पर ही उसकी मायना का भी निर्धारण करत हैं। उनकी हप्टि म राष्ट्रपति अधिनायक (despot) है तथा सविधान के अ तगत विशेष अवस्थाओं म वह एक अधिनायक या तानाचाह बन सकता है। श्री बनर्जी की दृष्टि म यह अधिवक्ता-वादो इध्टिकोण अस्यधिक सकीण एव विधिक होता है और अधिकादा सर्वैद्यानिक मामला की तरह यह इंग्टिनाण भी तथ्या के विपरीत होता है। " इसके ठीक विपरीत राजनीति के यथायवादी विचारका या राजनीति सास्त्रिया ना इप्टिकाण है। इनकी इप्टिम किसी देश के सविधान का केवल लिखित रूप ही नहीं होता है। अभिसमय एव परम्पराएँ जा सबधानिक नतिकता के नियम माने जाते हैं, सविधान का अत्यधिक महत्वपूण भाग होत हैं। अत सविधान की व्याख्या करते समय उसके बाह्य रूप का ही नहीं अपितु प्रशासकीय ययायता (Administrative realities) एवं उसकी आन्तरिक कायपद्धति की भी ध्यान में रखना चाहिए। इस मत का अनेक यायदाास्त्रियो न भी समधन किया है। अत सविधान की पूणक्पेण सवैधानिक परम्पराआ एव सवधानिक विधि कस दम म ही समभा आ सकता है। फलत राजनीति के यथापवादी विचारका की दृष्टि म देश की महत्वपूर्ण राजनीतिक सस्याओ का अध्ययन करते समय हम सविधान की केवल विश्द विधिक व्यवस्था का ही अध्ययन नहीं करना चाहिए अपित प्रयोगा, परम्पराओ, रीति रिवाजो अभिसमया का भी पूरी तरह से ध्यान म रखना चाहिए। य सविधान के अविधिक (non legal) नियम होते हैं, न कि अविधिक (illegal) नियम ।

राष्ट्रपति की ययाथ स्थिति जानने के लिए विगत 25 वर्षों म उसके ब्यावहारिक स्वरूप का अध्ययन वाछनीय है। पर जु पर्याप्त साहित्य उपलब्ध नहीं है जिस पर हम कोई निश्चित निष्कृप निर्धारित कर सके। केवल एक बार राष्ट्रपति पद के निर्धाचन के लिए सम्प हुआ है। विगत 25 वर्षीय सक्ष्मानिक इतिहास के बाधार

²⁴ Banerjee, D N Some Aspects of Indian Constitution, 1962, p 94

पर यह वहा जा सकता है कि मूनपूर्व तीन राष्ट्रपतिया एव वतमान राष्ट्रपति ने अपनी शक्तिया नी निधिक धारणा को मा यता नहीं दी है। अपितु व सभी सनधानिन अध्यक्ष ने रूप म काय करते रहे हैं। समदीय प्रणाली व मान्य सिद्धा त के अनुसार कायपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति क नाम पर ने डीय मित्रमण्डल परता है। यही अधिकास सविधा-निर्माताओं का भी मत था। व सारतीय सप्ट्रपति की ब्रिटिश काउन व सममक्त मानते थे। सवि गान के प्रारूप का प्रस्तुत करत समग डा मीमराव अम्बेडकर ने कहा या कि "मविधान द्वारा शासन के किस स्वरूप नी कल्पना की गयी है ? मारतीय सघ का अध्यक्ष सध का राष्ट्रपति नामक पदाधिकारी है। यह नाम हमें सयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की बाद दिलाता है। लेकिन दोना के गामा म समानता के अतिरिक्त अमरिका के प्रचलित शासन तथा प्रारूप म प्रस्तावित वासन म कोई समानता नही है । दोना म मौलिक भेद हैं । अमेरिकी राष्ट्रपति वायपालिका एव प्रशासन का प्रमुख होता है । 'प्रारूप क अधीन भाग्तीय राष्ट्रपति की स्थिति इगलैण्ड के सविधान के अत्रगत राजा जसी है। वह राज्य का अध्यक्ष है, शासन का नहीं । वह राष्ट्र का प्रतीक है, राष्ट्र पर शासन भारतीय राष्ट्रपवि नहीं करना। प्रशासन म उसकी स्थिति औपचारिक है। अपने मित्रया के परामन की मानते के लिए बाध्य होगा। वह न ता उनकी इच्छा क मिन्द्र काय करेगा, न कुछ कर सनेगा। जब तक मिन्या ना ससद म बहुमत है, भारतीय राष्ट्रपति का काई शक्ति प्राप्त नहीं है। अमेरिकी सामन कायपालिका एव व्यवस्थानिया के शक्ति प्रवक्तरण पर आधारित है। (सारतीय) मविधान का प्रारूप इस मिद्धात को स्वीकार नहीं करता है। ससदीय प्रणाली में उत्तरदापित्व पर अधिक वल दिया जाता है। इनकी अपेक्षा अससदीय प्रकाली में स्थामित्व पर अधिक वल दिया जाता है। प्रारूप समिति ने ससदीय कायपानिका क प्रावधान द्वारा स्थायित्य की अपेक्षा उत्तरदायित्व का अधिक महत्व दिया है। एक दूसरे अवसर पर कों अम्बेडकर ने कहा था कि 'ऐसा कोई मामला नहीं है जिसके' दारे म राध्यपित प्रधानम नी या उसके मि तमण्डल क परासदा क बिना काय कर सके।" 6 डा अम्बेडकर के इस मत का कि मारत का सविधान ससदीय प्रणाली की स्थापना करता है. अनक मदस्या न समयन किया था। उदाहरणाय, श्री कृष्णमाचारी ने कहा था कि (सवि धान) समा न राज्या व केंद्र में उत्तरदायी शासन के सिद्धा त को स्वीकार किया है। रे भी फ्रांचमाचारी ने यह भी कहा था कि सविधान का एक दाप यह बताया गया है कि कही भी राष्ट्रपति का सर्वधानिक अध्यक्ष नहीं कहा गया है, इसमे महिष्य

²⁵ Constituent Assembly Debates Vol VII, pp 31 33

²⁶ Ibid, pp 1157 1160

²⁷ Ibid , pp 834-36

म राष्ट्रपति की शक्तिया के बारे म स देह उत्प न होगा। राष्ट्रपति की स्थिति अमे-रिकी राष्ट्रपति की तरह नहीं है। राष्ट्रपति को तो प्रधानमात्री के परामश पर काय करना पड़ेगा जल वह निरन्दा नहीं हो सकता ।" 8 औं के सत्यानम का मत था कि भविधान सभा ने ससटीय प्रणाली की स्थापना वी है और इसी को आधार मानकर सम्पण सर्विधान रचा गया है। 29 डॉ राजे द्रप्रसाद ने जो सर्विधान सभा के अध्यक्ष धे एवं मारत के प्रथम राष्टपति बने, स्वय नहा या कि अमेरिका म कायपालिका एव ध्यवस्थापिका दोना ही निर्वाचित होती हैं और दोनो की समान शक्तिया होती हैं। ब्रिटिश प्रणाली म बशानुगत राजा होता है जो सम्मान एवं शक्ति का स्रोत है पर तु वह सभी शक्तिया का उपभोग नही करता। "हमे निर्वाचित राष्ट्रपति एव निर्वाचित कायपालिका मे सम्बाध स्थापित करना है और इस प्रवतन म हमने ब्रिटिश सम्राट की स्थित को राप्टपति की स्थित स्वीकार किया है। राप्टपति की स्थित सवधानिक राष्ट्रपति की है।' राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल का परामश मानने के लिए बाध्य है। जहा तक मुभे नात है सविधान मे ऐसा कोई स्पप्ट प्रावधान नहीं है कि राप्ट्रपति के लिए प्रधानम त्री की राय मानना जावस्यक है। परात् यह आशा की जाती है कि इगलैण्ड का राजा जिस प्रकार अपने मित्रया के परामश पर काय करता है, वहीं अभिसमय इस देश में स्थापित होगा और सविधान के शब्दों के कारण नहीं अपित स्वस्थ अभिसमयों के विकास के कारण वह सबैधानिक राय्टपति होगा।³⁰ भारत के प्रथम प्रधानमात्री प जवाहरलाल नेहरू ने भी समय समय पर यही मत व्यक्त किया है। उनके अनुसार, "हमारा सविधान अमरिकी प्रणाली पर जाधारित नहीं है अपित ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है। '31 एक दूसरे अवसर पर नेहरू जी ने कहा था कि हमारे दश का सविधान ससदीय प्रजात न की स्थापना करता है। ' ३३ इयलण्ड की ब्रिटिश ससदीय प्रणाली से अपने दीधकालीन सम्पक के कारण हम बिटिश ससदीय सस्याजा की हृष्टि से सोचने के लिए याध्य थे। 33 हमने ससदीय प्राणाली का चुनाव जान प्रमकर किया है क्योंकि हम इस प्रणाली स पून परिचित हैं। हमारी दृष्टि म नवीन परिस्थितिया हमारी परम्पराओं के अनुरूप हैं और यह प्रणाली अय दशा विशेष कर इगलण्ड म सफलतापुर्वक चलती रही है। 25 प्रारूप समिति के एक अप सदस्य भी कारैयालाल मणिकलाल मुशी ने सविचान सभा म बहा था कि सधीय सविधान समिति के

²⁸ Ibid, pp 956 57

²⁹ Ibid pp 965 66

³⁰ Ibid , p 988

³¹ Loksabha Debates, 5th July, 1952

³² Loksabha Debates 25th Feb , 1955

³³ Speeches of Jawahar Lal Nehru Vol VII, 1953 57, p 142

³⁴ Ibid pp 155 56

ा जापुरवक हासनत त्र

मारम्मिक अधिवसना म ही एक दो सदस्यों ने निरोध से यह तय हो चुका था कि हमारा के द्रोप बासन ब्रिटिस प्रणाली पर आधारित होगा और हमने अमेरिकी प्रणाली को अस्वीकार कर दिया था। इमलण्ड की कायपालिका सर्वाधिक शक्तियाली एव अल पिक नमनीय है, कायपालिका चक्ति मित्रमण्डल म निहित है जिसे निम्न सदत हा बहुमत प्राप्त होता है तथा सविमान के अधीन वित्तीय सक्तियों भी प्राप्त होती हैं।" स्पष्ट है कि सविधान तमा ने संबदीय प्रणाली की स्वापना की थी और डॉ अम्बेडकर की हिस्ट म सविधान के बनुसार राष्ट्रपति के लिए मित्रमण्डल के परामग्रीन काय करना व धनकारी है। 18

समय समय पर राष्ट्रपति की स्थिति के सम्बय म तीन विदाद जलन ह रहे हैं। अवकाश प्रहण करने के कुछ समय पूच हा राजे द्वप्रसाद ने सावजीनक क पानत व्याख्या है। सर्विधान में ऐसी कोई घारा नहीं है जो स्पट्ट घट्टा म मिनमण्डल के परामद्यानुसार ही कार्य करना राष्ट्रपति के लिए आवश्यक बनाती हो। इसलैण्ड की व्याख्या का अनुवसन करना हमारे निए आक्रयक नहीं है क्यांकि दोना देशा की परि स्यितियों में अतर है। अ

उनके द्वारा व्यक्त इन विचारों ने सर्वधानिक दृढ प्रारम्भ कर दिया। प्रस्मर विरोधो विचार प्रस्तुत किये गये। राष्ट्रपति को सवधानिक अध्यक्ष मानने वालो ने अपने पक्ष म निम्न तक प्रस्तुत किये हैं

- (1) वे डॉ अन्वेडकर डा राजे दमसाद एवं सविधान समा के अय सदस्ये के उपरोक्त उस्तिबात तकों को अपने समर्थन में उपस्थित करते हैं।
- (2) मिनमण्डल सामूहिक रूप से लोकसमा के मति उत्तरवायी है [अनु 75 (3)] 1
- (3) धासन की नीतियों के लिए राष्ट्रपति लोकसमा के प्रति उत्तरदायी
- (4) अनुच्छेद 78 के अ वगत प्रधानमंत्री का यह वायित्व है कि संधीय प्रशासकीय मामला एव विजान सम्बची निषयो (decisions) की सुचना उसके द्वारा राष्ट्रपति को दी जाय। यहा 'निषय सन्द का प्रयोग यह स्पष्ट करता है कि निषय मित्रमण्डल करेगा, न कि राष्ट्रपति। (5) राष्ट्रपति को कोई स्विविवेकीय सक्तियाँ प्रदान नहीं की गयी है बिनुच्चेद
- 35 Constituent Assembly Debates, p 984 36 Ibid p 974
- 37 मारतीय विधि सस्यान के उद्याटन-अवसर पर दिया गया नापण (नवम्बर 28,

74 (1) ।] मि त्रमण्डल का परामक्ष मानने के लिए राष्ट्रपति वाध्य है। स्मरणीय है कि राज्यपाल को अनुच्छेद 163 (2) के अ तमत कुछ स्वविवेकीय शक्तिया प्रदान की गयी हैं। राष्ट्रपति को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है।

(6) सविधान निर्माता भारत शासन अधिनियम, 1935 एव उसकी काय-पद्धति से प्रमादित थे। भारत शासन अधिनियम, 1935 के अतमत गवनर जनरस को प्राप्त सभी स्विविकीय शासिया नवीन सविधान में राष्ट्रपति को प्रधान नहीं की गयी है, यदापि राष्ट्रपति के सन्दम में यह व्यवस्था स्वीकार की गयी है कि वह मिन्नपञ्ज के परामर्थान्तार काय करेगा।

दूसरे पक्ष अर्थात जो राष्ट्रपति के लिए मिनमण्डल का परामक मानना आव इयक नहीं मानते, अपने पक्ष में निश्न तक प्रस्तुत करते हैं

- (1) अनुच्छेद 74 (1) मे यह कहा गया है कि प्रधानम त्री की अध्यक्षता मे एक मित्र परिषद होगी जो राष्ट्रपति को उसके कार्यों में परामक्ष देगी। इस या अप्य अनुच्छेदों में यह नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति के लिए मित्रसण्डल का परामर्श मानता व धनकारी है।
- (2) सिवधान द्वारा राष्ट्रपति को कुछ ऐसी क्षक्तिया दी गयी हैं जिनका प्रयोग उसे स्विविक से करना चाहिए। उदाहरणाथ—
- (क) अनुच्छेद 111 के अनुसार घन विधेयको के अतिरिक्त अ य विभेयको को राष्ट्रपति अस्वीकृत कर सकता है। प्रकृत यह है कि ससदीय प्रपाली में जब मिनिमण्डल कं समयन के बिना कोई विभेयक पारित नहीं हो सकता है, तो फिर राष्ट्रपति को नियेषाधिकार प्रदान करने की क्या आवश्यकता थी?
- (ख) अनुच्छेद 78 (ब) के अनुसार राष्ट्रपति को प्रधानमानी से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। इस शक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमानी के परामश से प्रयोग नहीं करेगा।
- (ग) प्रधानम नी का चुनन का अधिकार राष्ट्रपति को है। किसी दल के स्पष्ट बहुमत के अमाव मे राष्ट्रपति का विवेक ही इस निणय में निणियक हो सकता है।
- (य) यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति की हिन्द म नीति निर्देशक तत्वो के विपरीत है ता वह मि त्रमण्डल के परामध के विना ही उसे अस्वीकृत कर सकता है।
- (ह) राष्ट्रपति किसी ऐसे विषेयक पर जो पुन पारित विया गया हो, नियेशांपिनार का प्रयोग नहीं कर सकता। 38 इसका अथ यह हुआ कि प्रयम बार किसी विषयक को अस्वीकार करने की उसकी शक्ति वास्तिषिक है। सविधान द्वारा राष्ट्रपति को नियेधांपिनार देन का यही अथ है कि उसे इस शक्ति का स्विविक से प्रयोग करने की स्वत त्रता है।

620 | जापुतिर वासनत त्र

- (न) समद व त्रिपटन व प्रशात होने वाले नव निर्वाचना म मित्रमण्यत के पराजित हो । पर मित्रमण्डल द्वारा ससद को पुत्र विपटित करने सम्बन्धी परावद को अस्वीरार वरन क निए त्या राष्ट्रपति स्वत व मही है ? वस्तुत वह मित्र मण्डल की एसी बनतिन भांच ना बस्चीनार रस्त नी पूण धक्ति रपता है और मन्त्रिमण्डल के निर्माण में भी पूण स्वत य होगा।
- (3) तिटिस सविधान की परिस्थितियों निम्न हैं। अंत ब्रिटिस सविधान अनुसार मारतीय राष्ट्रपति का नाममात्र का अध्यक्ष मानमा उचित नही है। तिवि र्वे सर्विपान प्रयाद नेस मारत म अविश्वित ब्रिटिश अभितममा की कल्पना एवं अनुग्रम
- (4) मारतीय राष्ट्रपति निर्वाचित अध्यक्ष है जबकि बिटिश राजा बसानुगत है। निवाधित भारतीय राष्ट्रपति को क्यल नाममाथ का क्यास मान समभना भूल है।
- . (5) मारतीय संघीय प्रणाली में राष्ट्रपति से केंद्र व राज्यों के मध्य सम वय वर्ता के रूप म प्रमावद्याली भूमिका निमान की भागा की जाती है। यह सम्भव है कि यह इस भूमिका का निवाते समय अपने मिन्यव्यत की राम को स्वीकार न कर सके। उदाहरण क लिए केंद्र म किसी एक दल का बहुमत है और राज्य या राज्या म दूसरे दल का। क्या राष्ट्रपति को निसी राज्य म नामसान के राजनीतिक कारणों स प्रेरित ने डीय शामन के राष्ट्रपति धासन की स्थापना सम्बन्धी सुफाव को मान लेना चाहिए ? ऐसं अवमरो पर उससे स्विविक क प्रयान की आधा की जाती है।
- (б) पिछडी तथा परिगणित जातिया की दशा की जावने क लिए वायोग की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। सनियान म 'as be thinks fit' सन्श का प्रयाग किया गया है। ³⁰ सर्विधान निर्माताओं ने इस सम्बंध में रास्ट्यित को स्प-विवेकीय '1क्ति देना इस कारण आवस्यक समक्षा या जिनम कि राष्ट्रपति परिगणित जातिया के हिताप निष्पक्षनापुषक काय कर सके। अनुच्छेद 339 म as you think fit राज्या का प्रयोग नहीं किया गया है। इससे उपरोक्त मत की पुरिट होती है।
- (7) राष्ट्रपति को आज प्रदेश एव पबाव के लिए क्षेत्रीय समितिया निमुक्त करने का अधिकार प्रचान किया गया है। नया इस विक्ति का प्रयान भी उसे व द्वीय मि त्रमण्डल के परामर्थानुसार ही करना चाहिए ?
- (8) सविधान में स्वय्ट रूप सं राष्ट्रपति की स्वविवकीय शक्तिया का जल्लस 39 अनुच्छेद 340

न होने का यह अथ नहीं कि उस नोई स्विविकीय शक्तिया प्राप्त ही नहीं है। श्री के एम मुंबी के अनुसार राष्ट्रपति सिविधान को निष्ठाप्त्रवक कियावित करने तथा उमकी रक्षा एव सुरक्षा को श्रथ प्रहण करता है। ⁶⁰ अत वह मारत की एकता, कत्याण एव सुरक्षा के लिए उत्तरदायों है। इस वाथित्व के निवाह के लिए उसे स्व-विवेकीय राक्तियों प्राप्त है। इसके अतिरिक्त महत्वपुण मामलों में सर्वोच्च वायालय का परामक्ष तेने तथा सन्ट काल मं सविधान के अशो को निलम्बित करने के सदम मं उस स्विविकीय शक्तिया प्राप्त हैं। महाभिवक्ता (अटोनीं जनरल) की निप्रक्ति के सम्ब भ में उसे स्वविवेकीय अधिकार रहें। ⁶⁴

(9) यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाय कि राज्य की जनसरया का पर्याप्त माग यह वाहता है कि उस राज्य म बोली जान वाली किसी मापा को मायता दी जाय तो उस मापा को उस राज्य या उसके किसी माग मे शासकीय मा यता दी जानी चाहिए। " स्पष्ट है, राष्ट्रपति को यह शक्ति स्वविवेकानुसार प्रयोग करनी चाहिए।

(10) राष्ट्रपति पर सिवधान के उल्लंघन के लिए महामियोग लगाया जा सकता है। प्रश्न यह है कि जब सभी काय राष्ट्रपति मनि परिषद के परामशांनुसार करता है तो उस पर महाभियोग लगाने की व्यवस्था ही क्या की गयी है?

श्री के एम मुशी ने राष्ट्रपति की स्थिति की तकपूण समीक्षा की है। उसका सार निस्तवत है⁸⁸

'सविधान समा प्रारम्म से ही ससदीय शासन के पक्ष में थी। सरवार पटेल तया थी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने ससदीय प्रणाली का समयन किया था। केवल श्री के टी शाह अमरिकी दण की शासन प्रणाली के पक्ष म थे। इस मत को स्वीकार नहीं किया गया। सविधान समा का मत था कि म नीगण बहुनत में चे चुन जायें एव सविधान के अनुसार काम करे। परजु यह सब विचार उस समय यक्त किय मामे थे जब मिनिण्डल तथा राज्यति के सम्ब वी पर विचार नहीं ही रहा था। "

"सविधान समा का मत था कि राष्ट्रपति नाममान ना अध्यक्ष नही है। प जवाहरलाल नेहरू ने सविधान समा में स्वयं कहा था कि हम राष्ट्रपति की फ्रेंच

⁴⁰ उप राष्ट्रपति एव मात्रीगण केवल सविवान के अनुसार काय करने की शपय लेते हैं। अंत राष्ट्रपति और मित्रयों की अपय से दायित्व सम्बाधी भेद स्पष्ट है।

⁴¹ Munshi, K M President under the Indian Constitution 1967, p 35

⁴² अनुच्छेद 347

⁴³ श्री मुशी सविधान समा के सदस्य एव प्रसिद्ध अधिवक्ता थे । देखिए उनकी पुस्तक 'The President under the Indian Constitution, (1967)

⁴⁴ Ibid pp 2, 3 and 6

622 | आधुनिक दासनतन्त्र

राष्ट्रपति की मीति नाममान का बच्चक्ष नहीं बनाना चाहत। उसका पद महान् प्रक्ति एन अधिकार का है।" मुद्धी के अनुसार अधिकार (Authority) का अथ नाममात्र की सत्ता से नहीं है ।""

"डॉ बम्बेडकर मी राष्ट्रपति की स्थिति (position) के वारे म स्थिर एव स्पष्ट मत नहीं रसते थे। एक अवसर पर उन्होंने मास्तीय राष्ट्रपति को इगलण राजा के समकक्ष माना था 1⁶⁷ दूसरे अवसर पर उनके अनुसार राष्ट्रपति नामनाव अध्यक्ष है एव मित्रमण्डल के परामश्च पर ही नेवल काय करेगा 140 एक गीसरे अ सर पर डॉ अम्बेडकर ने भारतीय राष्ट्रपति को इगर्सण्ड क राजा की मीति ती शक्तियो—परामण देने, प्रोत्साहित करने एव चेतावनी देने—के अधिकार से युक्त

"संविधान समा के अनेक सदस्या की राय थी कि राष्ट्रपति को अधिक धर्मितयाँ दी जा रही है।" इसके अतिरिक्त ' हा अम्बेडकर एव डॉ अल्सारी स्वामी अय्यर के राष्ट्रपति के सम्ब घ म जो मत है वे जनके व्यक्तिगत मत हैं, न कि सविधान समा B 11150

''सिवधान समा मे दो बार यह प्रवन उठा या कि क्या राष्ट्रपति सिवधानानुसार राष्ट्रीय मिनमण्डल का परामदा मानने के लिए बाध्य है ? स्वय हा राजे प्रभाव में द्रिया या कि क्या राष्ट्रपति मन्त्रियण्डल की राय मानने की वाच्य है ? डा अस्वेडकर का मत था कि 'aid and advise' सब्द इस सब्द घ म पर्याप्त हैं। फिर भी हाँ राजे द्र प्रसाद ने इस बात पर बल दिया था कि हम सविधान में यह रंपष्ट कर देना इस पर डॉ अम्बेडकर ने कहा या कि सिवधान में राष्ट्रपति सम्बन्धी ment of Instructions (निवंशी) की व्यवस्था की जायेगी। परन्तु प्राक्ष को निर्देशी का विचार स्वीकाय नहीं था। ध

"इसरी बार श्री हरिविष्णु कामय ने यह मत ब्यक्त किया था कि सबिप यह कही स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रपति मिनमण्डल की राय मानने को बाध्य है। ब

⁴⁵ Constituent Assembly Debates, Vol IV, p 734

^{45 &}quot;Authority is something more than command something it combines with reason — Munshi K M op cit, p 7 48

⁴⁹ Ibid , Vol VII, p 1158

⁵⁰ Munshi K M op cit, p 9

⁵¹ Constituent Assembly Debates, Vol X pp 269 71

अं राजे द्रप्रसाद ने अपने अन्तिम मापण म यह कहा चा कि कुछ व्यक्ति राष्ट्रपति को अधिक दाक्ति देने की शिकायत करते हैं।"

"भी के एम मुबी के अनुसार सविधान निर्मातावा ने राष्ट्रपति को ब्रिटिश राजा के समकदा कमी नहीं भागा था, मले ही मारत में ब्रिटिश ससदीय प्रणाली को स्वीकार किया हो। अपने मल की पुष्टि में उन्होंने निम्न तक दिये हैं

(क) मिर्वाचित मारतीय राष्ट्रपति की स्थिति वशानुगत ब्रिटिश राजा के समान नहीं हो सकती।

(स) मारतीय राष्ट्रपति की स्थिति सुस्पष्ट सबैधानिक उपबाधी पर आधारित

है, न कि ब्रिटिश राजा की तरह ऐतिहासिक विकास पर।

(ग) मारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है लेकिन ब्रिटिश सम्राट पर नहीं।"⁵⁵

श्री मुशी के अनुसार राष्ट्रपति मिनमण्डल का परामर्थ केवल कार्यपालक चिक्तयों के सम्बाध में ही मानमें को बाध्य है। स्वविविकीय चिक्तयों के सम्पादन म मिनमण्डल का परामश व घनकारी नहीं है। कुछ मामलों में राष्ट्रपति सीधे अर्थात् मिनमण्डल के परामश विना ही काय कर सकता है, जैसे—

(क) मित्रमण्डल के न होने की अवस्था में 1³⁶

(ख) जब राप्ट्रपति परमाधिकार का प्रयोग कर रहा हो।

(ग) जब देश सकट मे हो।

(घ) जब सविधान को खतरा हो।

(ङ) जब रायथ के अनुसार आचरण करना आवश्यक हो।

'सिविधान में अनेक उपवाधों में राष्ट्रपति की शक्ति एवं उसके सदम में ऐसे शब्दा का प्रयोग किया गया है जिनसे राष्ट्रपति में स्वविवेक का निहित होना स्पट्ट होता है। गैंसे अनु 123, 347, 332, 356, 357 में 'is satisfied' शब्द, 'is of opinion' [अनु 124 (3)], 'consent' (अनुक्छेव 127) 'determine (अनु 128), 'deem necessary [अनु 124 (2)] 'decision' (अनु 103) 'pleasure' [अनु 72 (2)], 'previous sanction' (अनु 304 एवं 309) आदि।"

श्री मुशी के बनुसार, "राष्ट्रपति की कुछ श्राक्तियाँ मात्रीमण्डलेत्तर (supra ministerial) हैं। ये ऐसे मामले हैं जिनम मात्रिमण्डल की राय एव परामश पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जैसे—

⁵² Constituent Assembly Debates, Vol XI, p 988

⁵³ Munshi, K M op cit p 13

⁵⁴ लेकिन ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि पहत्याम के पक्चात भी मिन-मण्डल नवीन मित्रमण्डल के पद ग्रहण करने तक काय करता रहता है।

- (क) सदन का विश्वास प्राप्त न कर सकने वाले प्रधानमानी एव मिनमण्डत को पदस्यूत करने के सम्बाध थे,
- (स) जनता का सही जयों म प्रतिनिधित्व न करने वाली लोकसमा के विष टन के सम्बाध म,
- (ग) सकट काल म मन्त्रिमण्डल का देश की रक्षा में असफल रहन पर सर्वोच्च सेमापित की शक्तिया क लपयोग के सद्य घ म ।'

मुशी का मत है कि राष्ट्रपति वो जनता के प्रति एवं मिनमण्डल को सगर के प्रति उत्तरदायी ठहराया गया है।" अत जावरयक्तानुसार राष्ट्रपति, श्री सथावम कं शब्दी में, सभी सक्तियों का प्रयोग कर सकता है। सविधान निर्माता राष्ट्रपति की राष्ट्रीय एकता की रक्षाय एवं गजनीतिक शक्ति वनाना बाहते थे। उमे वे दलीय व्यवस्था से उत्तर रख कर सविधान वे रक्षाक का एन श्री के इच्छुक थं। उमे वे रक्षीय व्यवस्था से उत्तर रख कर सविधान वे रक्षाक का एन श्री के इच्छुक थं। उस वे इस्त्रिय सबसीय सोकता है। अ

उपरोक्त विस्तेषण सविधान क उपव वा की विधिव एव तकपूर्ण व्यास्या पर आधारित है। व्यवहार में विगत 25 वर्षों में राष्ट्रपतिया ने सवधानिक अध्यक्ष की भूमिका निमायी है। प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजे तप्रसाद वर्श के प्रमुख एव गणमा य नेता थे। उन्होने अपने राष्ट्रपतित्व-काल म बास्तविक शक्तियो क उपमोग का कमी प्रयत्न नहीं किया और सदव मिनमण्डल के परामर्शानुसार ही काप किया था। हि द कोड विल पर उन्नेन मन्त्रिमण्डल को अपन निणय परपुत्रविचार के लिए कहा था। यह मित्रमण्डल का परामण था, न कि जादेण । फलस्यमप मित्रमण्डल न हिंदू कोड विल को अपन मूल रूप म पारित नहीं किया। डा राजे द्वप्रमाद न गम्भीरतापुनक नाममाप्र या सबैधानिक अध्यक्ष की भूमिका निनायी थी । यदि मि तमण्डल स व असहमत रहे तो भी उन्हाने मि त्रमण्डल-प्रधानम त्री-ना कमी विरोध नही किया। अतः राष्ट्रपति राजे द्रप्रसाद न सबधानिक अध्यक्ष की भूमिका निमान हुए स्वस्य अभिसमय का निर्माण क्या था। परवर्ती राष्ट्रपतिया डा राघाकृष्णन् डॉ जाकिर हसन एव थी वी वी गिरि न उसी का अनुसरण रिया है। यह अभिसमय मारत के सविधान पी मुल भावना एवं सामा य योजना क अनुरूप ही है। राष्ट्रपति को यथार्थ शक्ति देने वा अय है एक म्यान म दा तलवार (प्रधानमानी एव राष्ट्रपति) । किर राष्ट्रपति अप्रत्मक्ष रीति से निर्माचित है। प्रत्मक्ष रूप स निर्याचित एव निरन्तर समुद्र के प्रति उत्तरनायी नासन-व्यवस्था म अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित राज्याध्यक्ष को चास्त्रजिक शक्तियां प्रदान करना लानत न पर रोक (brake) नगान क समान होगा । यही नहीं, मारतवर म बहाँ व्यक्ति-पूजा नी परम्परा समाप्त नहां हुई है शक्तिनासी राष्ट्रपति ना अथ निरक्सताम के विकास हेनु अवसर प्रतान करना है । जहाँ तक विधेयरा नी

अस्वीकार बरने की द्यक्ति का प्रश्न है, इसका प्रयोग अमी तक केवल एक बार 1954 ई म किया गया है। 8 मान, 1954 को सदद ने पंप्यू राज्य—पिट्याला एव पूर्वी पजाब राज्य सप—मा विनियोग विधेयक पारित किया था। पर तु 7 मान को ही पेप्यू म राप्ट्रपित द्यासन नो समाप्त करने की घोषणा की जा चुनी थी। सदद को उक्त विधेयक पारित करने का अपिकार ही नहीं था। स्पट है, इस मामने मे राष्ट्रपित म स्विवेयक सारित करने का अपिकार ही नहीं था। स्पट है, इस मामने मे राष्ट्रपित के सम्बन्ध मे है। श्रोमती इन्दिरा गाँधी के परामश्च पर ही राष्ट्रपित गिरि ने लोकसमा यो विधित किया था एव 1971 ई के मध्यावधि चुनाव हुए थे। अत इस सम्बन्ध म यह घटना एव असिसमय है जिसका मिल्य मे पालन किया जायेगा। यह अन्य ससदीय देशों में रनीकृत परम्परा के भी अनुरूप है।

राप्ट्रपति कं सज्ञक्त व्यक्तित्वधारी होने की दशा म स्थिति मिन हो सकती है। निर्वाचित प्रतिनिधि होने के कारण वह मिनमण्डल को अनेक प्रकार से प्रमाधित कर सकता है। इसके अतिरिक्त ससद म किसी ची दल के स्पट बहुमत के अमाब म प्रधानम नो की निर्मुक्त में उसकी मूमिका निश्चय ही निर्णायक होगी। एसी स्थिति म उस प्रधानम नो कं चयन म पर्याप्त स्वत नता प्राप्त हा जायेगी और वह स्वेच्छा पूचक प्रधानम नो को चुननर मिनमण्डल के संगठन एवं स्ववर्ष को प्रमाधित कर सबेगा।

अ'त में निष्कप के रूप में हम यह कह सकते हैं कि मारतीय राष्ट्रपति वास्त विक कायपालिना नहीं है। उसका पद सम्मान एव प्रभाव का है। वह अपने दीघ राजनीतिक अनुभव एव सबधानिक शक्तिया से मिनम्ब्बल को परामश व चेतावनी वे सकता है एव उससे सुचना प्राप्त करके प्रभावित कर सकता है। उसका पद सिद्धात म शक्ति का है परातु ब्यवहार में प्रभाव (influence) का है, और यह प्रभाव मी अस्य कारान एव निणायक है। यदि राप्ट्रपति वलीय हस्टिकोण का परित्याग करके सवैयानिक कारों म पूण निष्यक्षता का प्रदश्चन करता है तो भारतीय सबधानिक शासनत म सह प्रभावशाली एवं सम्मानीय भ्रमिका निभा सकेगा।

भारतीय के दीय महित्रमण्डल

के द्रीय मित्रमण्डल वास्तविक सधीय कार्यपालिका है। राप्ट्रपति को अपने दायित्वों के सम्पादन में सहायता एवं परामक्ष देने के लिए सविधान के अनुस्देद 74 के अनुसार प्रधानमंत्री की अच्यसता में एक मित्रमण्डल की स्थापना की व्यवस्था है। मित्रमण्डल द्वारा राप्ट्रपति का दियं जाने वाले परामक्ष की किसी यामाल्य द्वारा अज्ञान सम्बन्ध की किसी यामाल्य द्वारा प्रधानमंत्री की निम्नुक्ति एवं प्रधानमंत्री के परामध्य पर अप मित्रों की निम्नुक्ति का प्रावधान है। मित्रमण्डल सामूहिक रूप संतोकसमा के प्रति उत्तरदायी होता है। मात्रीयण राष्ट्रपति के प्रसाद पय तही पदा-

रूद्र रहते हैं। यदि कोई सात्री अपनी नियुक्ति के 6 माह ने जीवर ससद क दो सदना म से विसी एक सदन की सदस्वता प्राप्त करने य असपन रहना है तो हा अविध के पूण हात ही उसे मात्री पद से हट जाना पडता है। या राष्ट्रपति मित्रमण्ड को अपने पद एव गोपनीमता की धापय दिलाता है। मित्रिया के बतन एव मत्त समय समय पर ससदीय विधि हारा निश्चित किये आते हैं और जब तक ससद हारा हकते निर्मारण न किया जाय उस समय तक भी अविध के लिए सियान के दितीय शब्दून (Schedule) म इसने व्यवस्था की गयी थी। 1952 ई म ससद ने मन्त्रिया के बेतन

एव मत्ता अधिनियम द्वारा प्रस्येक मन्त्री का वेतन एव मत्ता निर्पारित कर दिया

गया है।

के द्रीम मित्र परिषद ये तीन प्रकार वे मन्त्री होते हैं। प्रथम, मित्रमण्डलीय स्तर के मात्री। यह अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं और मित्रमण्डल की बठकों में मांग लेते हैं। हितीय, राज्य-मात्री (Ministers of State) जो कमी-कमी स्वतः त्र रूप के किसी विभाग के अध्यक्ष भी होते हैं पर खामा यत विभागीय मात्री के अध्यक्ष काय करते हैं। इह सम्बन्धिय मामांग र विकार के समय मित्रमण्डल के अध्यक्षिमों में आमीत्रत किया जाता है। ततीय अधी उप मित्रमा (Deputy Ministers) की अमित्रमा में आमीत्रत किया जाता है। ततीय अधी उप मित्रमा (Deputy Ministers) की है। उपने काय प्रमान स्वाप्त होते हैं। इसके अधिवेशमों

मिषिव भी होते हैं। वे क्सिी प्रकार की शक्ति का उपभाग नहीं करते हैं।

मारत म उप-प्रधानमानी का पथ भी रहा है। प्रथम उप प्रधानमानी सरवार

बल्लममाई पटेल था। उनकी मृत्यु के पश्चात यह पद समान्त हो। गया था। थी
लालवहादुर शास्त्री के प्रधानमात्रित्व काल में थी। सोगरवी देसाई की पत लय

लालवहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल मं श्री सोगरत्वी देसाई को पुत उप
प्रधानमंत्री बनाया गया । श्री मोरारजी देसाई के हटन के परचात यह पद पुत
समाप्त हो गया है। वस्तुत यह पद तभी निर्मित किया जाता है जब मिनमण्डल मे

56 इस प्रावधान के अधीन सबधी डा जान मवाई, सी डी देशमुल चत्रवर्ती
राजगापालाचारी, श्रीप्रवाय, श्री स्वर्णसह, पण्डित यांवि द्वाल्यन पर्ता, श्री एस
सी चामका एवं सीमती इदिया गाँधी को मंत्री बनाया गया और बाद मं वे

सी स्वितना एवं सामती हो वटा मोधी की मुझी बनाया गया और बाद म वे व्यवस्थातिक के सदस्य निवर्शनित हुए थे।

57 स्वन भूना के तुरत्व परवात भीन परिषय (ministry) एवं मिनमण्डल (cabi net) को वेद हतना स्पष्ट नहीं था। अधानम भी को छोड़कर सभी मिनमों का स्तर समान था। 1949 ई अ श्री गोधानस्वाभी आपगर को मिनमण्डलीय सायत्व के समान था। 1949 ई अ श्री गोधानस्वाभी आपगर को मिनमण्डलीय सायत्व के समान था। प्रतिवदन दने के लिए बावैध हुए थे। उहान इस प्रतिवदन में मिनमण्डलीय सायत्व के बाविध का मिनमण्डलीय सायत्व के बाविध को सम्बन्ध मिनमण्डलीय स्वाप्त के बाविध को प्रतिवदन दिया था। फलत नवीन सविधान के बाविध मिनमण्डलीय मानी एवं 5 राज्य मिन्युक्त किये थय था।

58 भारत के उपमात्री ग्रेट दिटेन के ससरीम सचिव या अवर सचिवा (कनिष्ठ मत्रिया-Junior Ministers) ने समक्ष होते हैं। राजनीतिक दृष्टि से प्रभावशाली कोई वरिष्ठ नेता श्वामिल होता है। उपरोक्त दोना उदाहरण इसका प्रमाण है।

ब्रिटिस मिनमण्डल की माति भारत में भी बा तरिक मिनमण्डल (Inner Cabinet) का विकास हुआ है। प जवाहरलाल नेहरू के प्रवानमित्रत काल में प्रारम्स म नेहरू, पटेल, आजाद आ तरिक मिनमण्डल का निर्माण करते थे। सरदार पटेल की भृरपु के पश्चात मीलाना आजाद का नेहरू पर अधेताह्र प्रभाव अधिक बढ़ गया या ता त्या गोविष्टबस्लम पत एव लालबहाषुर शास्त्री आवरिक मिनमण्डल के सदस्य बन गये थे। आ तरिक मिनमण्डल का कोइ सवैधामिक आधार नहीं है। प्रधानमानी के विश्वस्त एव प्रभावशाली सहयोगी मिनयो की अनीपचारिक बठक एव विचार विभन्न को ही आ तरिक मिनमण्डल की सजा दी जाती है। श्री कृष्ण मनन, श्री न दा, श्री चह्नाण एव श्री जगजीवनराम समय समय पर आतरिक मिनमण्डल के मानवाली सदस्य रहे हैं। प्रधानमानी श्रीमती इंदिरा गांधी के काल म स्वर्गीय ही पी घर, स्वर्गीय कुमारमणलम, श्री जमाशकर दीक्षित आतरिक मिनमण्डल के सदस्य हो है। सामा यत प्रधानम नी, गृहम की वित्तम त्री एव सुरक्षा मानी आ तरिक मिनमण्डल के सदस्य हो है। सामा यत प्रधानम नी, गृहम की वित्तम त्री एव सुरक्षा मानी आ तरिक मिनमण्डल के सदस्य हो है। है। है है।

के द्वीय मित्रमण्डल के सदस्यों नी सरया औसतन 15 होती है। मित्रमण्डल विमिन्न समितिया के माध्यम से अपने कार्यों नो सम्पादित करता है। दस स्थायी समितिया है। इतम मुख्य हैं—आधिक समिति, मारी उद्योग समिति, सुरक्षा, वैदेशिक, सत्तरीय एवं विधिक मामला सम्बाधी समितिया, सुचना एव ब्राडकास्टिंग समिति, मानव सक्ति एवं विधिक मामला सम्बाधी समितिया, सुचना एव ब्राडकास्टिंग समिति, मानव सिक्ति सिक्ति (Man Power Committee), ब्रज्ञानिक चिमित तथा नियुक्ति समिति । यह विभिन्न समितिया सम्बाधित मानवों पर नेवल विचार विमन्न ही मही करती वरन निपय भी लेती है। इनके निपयों को मानवण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। सिज्ञमण्डल इन निणयों को सामायत स्वीकार कर लेता है। सिमित्यों को अध्यक्षता अधिकाश मामलों में प्रधानम त्री हारा ही की जाती है। अत यह सिक्तिया पर्यान्त सिक्तालों होती हैं। आलोचको का मत्त है कि ये विभिन्न सिमित्या मानियाज्ञ की प्रतिस्थ वीं सस्थाएँ वन गयी हैं। यह स्वस्थ परम्परा नहीं है। विभिन्न सितिया का सगठन एकन्या नहीं है। नियुक्ति समिति म जहां केवल तीन सदस्य हैं, वहा नारी उद्योग सिमिति म प्रदा केवल तीन सदस्य हैं।

काय एव शक्तियाँ

मारतीय मित्रमण्डल ब्रिटिश मित्रमण्डल की माति देश की नीति निर्धारित करता है, वित्त पर नियत्रण रखता है और व्यापक कायपालन एव प्रशासनीय शक्तिया का उपमोग करता है। यही देश की कायपालिना है।

विभिन्न मामको से सम्बचित सामान्य नीति का निर्माण मित्रमण्डल करता है तया उनसे सम्बचित विभागो एव मत्रालय के कार्यों का समावय करता है।

विधायी कायक्रम को निर्धारित करता है। अधिकाश विधेयक मनियो द्वारा ही प्रता वित निये जाते हैं। लोनसमा म मित्रमण्डल का बहुमत होता है अत मित्रमण्डल के सहयोग के अमान म व्यक्तिगत सदस्या के हारा प्रस्तुत निषयको का पारित होग कित ही नहीं बरन अवस्मव होता है। वित्त विधेयको पर मित्रमण्डत हो एकाधिकार प्राप्त है। वापिक वजट-आय व्यय प्रवत्र-यित्रमण्डल के द्वारा प्रस्तुव किया जाता है। नवीन करा एव पुराने करा के उमूलन सम्बंधी प्रस्ताव भी मात्र मण्डल द्वारा ही किय जाते हैं। देश की विदश्व गीति को भी मि नमण्डल ही निर्धारित करता है। देश क सम्मूण प्रशासनिक ढाँचे पर मित्रमण्डल का नियत्रण होता है। राष्ट्रपति के नाम पर की जाने बाली नियुक्तियां मिनमण्डल के हारा ही प्रस्ताबित की जाती हैं अर्चात राज्यवास विदेशों म राजदूत, सभी आयोगा क अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्तियाँ मित्रमण्डल द्वारा की जाती हैं।

मन्त्रिमण्डलीय उत्तरवाधित्व

मारतीय मिनमण्डल सामूहिक रूप से लोकसमा के मित उत्तरदायी है। भारताथ वा नगण्यत पात्रवण पात् इतका थह जय हा भागा भागाव्य जार एक राज्यात के अधादम्बर व ही रह सकता है। मारत में जारवायित्व का आधार संविधान है। असी नमण्डलीस स्वार-वायित्व निम्न प्रकार के हैं

(1) सामृहिक उत्तरदायित्व अर्थात समद कं प्रति सम्पूण मिन्मण्डलका उत्तर-वायितः । मि त्रमण्डल व्यवहार म लोकसमा के प्रति सामूहिक रूप से जत्तरतार्थ धारपा । या वर्गान्य प्रशास है । राज्यसमा में यदि मित्रमण्डल द्वारा प्रस्तावित कोई विषेयक विर जाता है तो पण्डल को त्यागपन देने की आवश्यकता नहीं है। पर तु लोकसमा किसी प्रस्ताव पाका का प्राचित्रक कर देती है या मित्रमण्डल के विरद्ध अविस्तास का प्रस्ताव ए भाव जरूपाइए कर पार है का का जाता है जा किसी विमाम की अनुदान माम की अस्त्रीकृत कर देती हैं, तो सा मित्रमण्डल को त्यामपत्र देना पडता है। तस्त्रण मित्रमण्डल एक साथ पद ग्र करता है और एक ताय पद त्याय करता है। एक मंत्री के प्रति अविश्वास का ३ करता ह शार पुत्र वर्ष के विरुद्ध अविस्वास होता है। एक मन्त्री हारा प्रस्तुत प्रस्ता राष्ट्रभ मा भगवा माना आता है। यही कारण है कि मीति निययक मायलो पर ता नाम्का भा नामा । सम्प्रम मित्रमण्डल विचार करता है। यदि कोई मित्री मित्रमण्डल की नीति से

⁵⁹ अनुष्टेद 75। मित्रमण्डलीय उत्तरदायित्व का आधार मारत म् संविधान है अनुच्छद । ३ । भा भगणकाम क्रान्सामस्त ४ । कामार मारत म धावधान ह जबिक ग्रेट त्रिटेन कराडा, जास्त्रीत्वा एवं दक्षिणी क्रफीका के सर्विषान उत्तर-जबाक १८ ११८न २ गाठा, जास्तुकार्या एवं पाटाणा वकाका क सावधानं उत्तर दापित्व के सम्बन्ध में मीन हैं। इन देशों म मिं त्रमण्डलीय उत्तरदाणित्व वाम दायरव क सम्बंध भ भाग हु। ६२ ६७। भ मा अभण्डलाथ उत्तरसायरव जान समय पर आधारित हु। इसके निपरीत आयर गणराज्य, नेतुय एवं पत्तम क्रेंब समय पर आधारत हु। ३०७ १४७५० वायर १४५१७४, चतुन एव ४४४ १०५ मणराज्य, जापान, वर्मा एव यूगास्ताविया के मविधानों में उत्तरदायित का स्पट उल्लेख किया गया है।

असहमत होता है तो उसको तुर त पद-त्याम कर देना चाहिए। 16 यदि म नी पद-त्याम कर तेना चाहिए। किसी म नी द्वारा साव-नहीं करता है तो उस उस नीति का समयन करना चाहिए। किसी म नी द्वारा साव-जनिक रूप से एसा कोई यक्तव्य नहीं दिया जा सकता जो मिनमण्डल की स्थीकृत नीति के विपरीत हो। न वह अपने सहयोगिया से परामश किये विना शासन को और से कोई आदवासन हो दे सकता है। यदि कोई म नी शासन की नीति में असहमत है सी प्रधानमंत्री उसे त्यागपन बेकर पद से पृथक हो जाने के लिए कह सकता है। 1

(2) सामूहिव उत्तरदायित्व का यह तात्यय भी नहीं है कि मिन्नण्डल किसी मात्री के अनुचित एव कुशासन सम्बन्धी कार्यों का समयन करें और न मानी के किसी भट आचरण के लिए सम्भूण मिन्नमण्डल उत्तरदायी ही होता है। यह मानी का व्यक्ति गत उत्तरदायित्व होता है परातु सविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। मिन्नमण्डल के विद्य अविद्यास प्रकट होने पर प्रमानमात्री को क्षसमा को विषटित करने तथा नदीन निर्वाचन की माग कर सकता है जिसे राप्ट्रपति को स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि नवीन निर्वाचन को माग कर सकता है जिसे राप्ट्रपति को स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि नवीन निर्वाचन मानी मानिस्म को पुत बहुमत प्राप्त हो जाता है तो वह पदा- इस रहता है अपया उसे पद-स्थाग करना पडता है।

(3) इसके अतिरिक्त म नी राष्ट्रपित के प्रसाद-प्यात ही अपन पद पर रह सकते हैं। राष्ट्रपित किसी भी म त्री को पदच्युत कर सकता है। ⁶³ यह विधिक दिस्पति है। व्यवहार म ऐसी दिस्पति के उत्पान होने की कोई सम्मावना नहीं है। कोई भी राष्ट्रपति बहुमत हारा सर्माधत मानी से प्रधानम नी के परामख के बिना त्यागपन देने अथवा पदत्याग सम्बंधी आदेश नहीं से सकता। यदि राष्ट्रपति इसके विपरीत काय करता है तो सर्वधानिक सकट के उत्पान होने की हर सम्मावना रहती है। इस व्यवस्था का केवल यही एक व्यावहारिक मूल्य है कि मानमण्डल का यदि कोई सदस्य प्रधान

⁶⁰ श्री वी वी गिरिन श्रम यायालय के निजय से असहमत होने के कारण तथा सी डी देशमुख ने बस्बई के प्रश्न पर के द्वीय मिन्निप्त से त्यागपन दिये थे। श्री सुबहाण्यम एक श्री अलगेसन ने (फरवरी 1965 ई) भाषा के प्रश्न पर त्यागपन दिये थे। विसे ये वाद मंदन दोनों ने जन्म त्यागपन वापस ते लिये थे श्रीर अपने पदा पर वन ते तह से होनों ने जन्म त्यागपन वापस ते लिये थे श्रीर अपने पदा पर वने रहे थे।

⁶¹ सबश्री पणमुख चट्टी, जॉन मयाई, स्थामाप्रसाद मुकर्जी के सी नियोगी, एच सी मामा, माहनवाल, अजितप्रसाद जन एव कृष्ण मेनन ने प्रधानम नी के सकेत पर त्यागपन दिये थे।

⁶² मूदडा काण्ड के लिए श्री टी टी कृष्णमाचारी न अपने को उत्तरदायी मानते हुए व्यक्तिगत रूप से त्यागपत्र दिया था।

⁶³ इसका एक अर्थ यह मी है नि मानी लोकसमा के विषटित हो जाने के पश्चात मी मानी रह सकत है। मिनिमण्डल अपने पद से पश्च्युत होने या त्यागपत्र दने पर ही हटता है।

म भी की बाना का पालन नहीं करता तो प्रधानम त्री राष्ट्रपति को ऐसे मत्री को पदच्युत करने ना परामश दे सकता है।

(4) राष्ट्रपति के नाम पर किये जाने वाले सभी कार्यों के लिए मिनमण्डल का विधिक उत्तरदायित्व होता है। अनुच्छेद 77 (2) के अधीन राष्ट्रपति के नाम पर दिवे जाने वासे आदेश एव निरंश राष्ट्रपति द्वारा इस सम्बंध म निर्मित नियमों के वर्षान अधिकृत होते हैं और इस आधार पर जनके विरुद्ध आपत्ति नहीं को जा सकती कि वे राष्ट्रपति डारा जारी नहीं किये गये हैं। अनुकाद 361 के अनुसार राष्ट्रपति क नार्यो को राष्ट्रपति के नाम पर सम्पादित करने के लिए मास्त सरकार उत्तरसायी है। इन उपव था के जनुसार मात्री राष्ट्रपति के कार्यों क लिए विधिक रूप से उत्तरवायी होते हैं। ब्रेट ब्रिटेन म राजा के नाम पर दिया गया आदश तभी वैध माना जाता है अब किसी मनी हारा उस पर प्रति हस्ताक्षर किये गये हो । स्पट है कि ब्रिटिश राजा मिनमण्डल के परामण पर काय करता है। मारतीय संविधान द्वारा स्पष्ट स्थ ते विधिक उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया है परंचु Aid and Advice' व भारतमा अस्य स्थानमञ्जू स्थान अनुस्कृत रहे (2) एवं 361 की स्थानमा करके सिवधान निर्माताओं ने विधिक उत्तरवायित्व को सुनिविचत कर दिया है। है।

मिनमण्डलीय उत्तरदायित्व पर वॉ अम्बेडकर के विचार निम्नवत हैं 'हमार सर्विधान में सामूहिक उत्तरसायित्व के सिद्धान्त को स्थान दिया गया है। अव प्रधान वाषवात न वाहारून वाहरूबात को जो किसी विशिष्ट समुदाय का सदस्य हो अपना प्रधानमंत्री और उसके दल के नीति विषयक मूल सिद्धाती से असहमत सदस्य को ने भारत वा जार कार्या । किसी भी अवस्था म राष्ट्रपति मित्रमण्डल के परामक्ष के विना काय नहीं कर सकता। विधा गांव गुरा १४ १०००। , के पालन से सम्मव है। प्रथम कोई भी व्यक्ति बिना प्रधानमनी के परामस के सामूहिक उत्तरदायित्व की रक्षा दो सिद्धा तो म नी निवुक्त नहीं किया जाना चाहिए। द्वितीय यदि प्रधानमधी किसी मंत्री स पदच्युत करने की माग करता है तो उसे मनी नहीं बना रहना चाहिए । सामृहिक उत्तरदायित्व के आदछ की उपलिष तभी सम्मव है जबकि मनियो की नियुक्ति एव उनको पदच्युत करना प्रधानमनी का अधिकार हो। पेरें व्यक्ति की मनी नियुक्त करता है जो उसके योग नहीं है तो व्यवस्थापिका प्रधानम त्री यदि किसी

⁶⁴ सिवधान समा म यह प्रस्ताव किया गया वा कि राष्ट्रपति के लिए निदेस नियमा संबंधान समा म यह नरवाय क्या प्रथा पा क्या राज्या क स्वर्थ गर्दस्य कार्व्य गर्दस्य कार्व्य गर्दस्य स्वयंत्र विकास वर्षा होता चाहिए बार जवाजन ना धारा १२०० २ व बारत साक्षन बाधानपन की तरहूं मिजिमण्डल में अन्तसंस्थक सदस्या को सामिल करने वर बत होने का का तरह मात्रमण्डल में अल्पाष्ट्यक एप्टार्ग का खामल करन पर बल दन वा मुभाव दिया गया था। इसी सदम में हा अम्बेडकर ने सामूहिक उत्तरदायित युभाव (दया पदा था। १ था। ५ ६म न ०। जन्त्वकर न धायुम्हरू उत्तरसावस्य की व्यास्या की यी। सीमाम्य से यह प्रयत्न असफल रहा। यदि यह नियम स्वीकृत का व्यास्त्या का था। तानाण ए पर उपन अपण अठक पर्छ। याद यह ानवम स्वाकृत हो गया होता तो सामूहिक उत्तरदायित्य वा सिद्धात व्यस्त हो जाता और श पण हाता आ जाता है। मित्रमण्डल की स्पिति के दीय न रहती।

अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके उस प्रवानमानी एव मानी दोनो सही मुक्त हो सकती है। 15

मित्रमण्डलीय उत्तरदायित्व के सिद्धात का विकास इगलैण्ड मे हुआ है। इस सिद्धात के फलस्वरूप ब्रिटिश राजा के वे म त्री जो उसके ही प्रति उत्तरदायी होते थे, राष्ट्र के सेवक वन गये हैं। पहले व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का विकास हुआ है। मार-तीय सर्विधान निर्माता इस सम्ब ध मे ग्रेट ब्रिटेन से ही प्रमावित थै।

मारत मे सामूहिक मिनमण्डलीय ज्तरवायित्व के किया वयन के सम्बाध मा श्री के बी राव का कवन है कि "वीमर सविधान (Wemer Constitution) के जनक प्रज (Pruesz) के इब मत को भारत ने सिद्ध कर दिया है कि सामूहिक जत्तरवायित्व एक अम (myth) है। मिनयों को अनक ऐसी व्यक्तिगत भूजों को, जिनके
फलस्वकृष इंग्लैण्ड मे मिनयों को त्यागपन प्रस्तुत करने पड़ते, प्रधानमनी ने यह कह
कर कि वे जनकी पूरी जिम्मेवारी वहन करते हैं, हवा म उड़ा दिया है। प्रधानमनी के
इस प्रकार कहने का यह जब हुआ कि यह मामला प्रधानमनी अर्थात मिनमण्डल की
प्रतिष्ठा का प्रश्न है और लोकसमा के बहुमत का प्रयोग मामले पर मावी विवाद को
रोकने के लिए किया जायेगा। "" "इंगलैण्ड मे सामूहिक जत्तरवायित्व विमिन्न परि
स्थितिया एव शक्तिका का परिणाम है, न कि जनके कारणों का, परन्तु मारत मे हमने
परिविधितयों का अनाव है। " अर्थात यहा सामूहिक जत्तरवायित्व के विकास की

डॉ राव के उपरोक्त मत को पूणक्ष्येण स्वीकार नहीं किया जा सकता। सामूहिक उत्तरदािधत्व की जिन परिस्थितियो एव शक्तियो की ओर वे सकेत कर रहे हैं
वे है मारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एव उसका इतिहास, जिसका परिणाम है मारत की
स्वत तता और स्वत नारत का लोकत नीय गणत न्वारमक सविधान । सविधान
से ससवीय प्रणाली को स्वीकार किया गया है और ससदीय प्रणाशी की सविधिक
संचक्त विशेषता सामूहिक उत्तरदाियत है। इसका स्पष्ट उत्तेख सविधान म किया
गया है। राष्ट्रपति के सहायताथ एव सहयोग के लिए मनिमण्डल होगा और वह
सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा—यह उपव घ ही ससदीय प्रणाली की स्थापना
करता है। सर्वोच्च यायालय के अनुसार हमारा सिवान संधीय होते हुए भी ससदीय
प्रणाली की स्थापना करता है " इंग्लैंड की माति मारत म मी कायालिया
व्यवस्थारिका के तथ नण में काय करती है। राष्ट्रपति नाममान की सवधानिक कायपालिका है। सर्वावक कायवालिका शक्तिया मनिमण्डल में निहित हैं। अत

⁶⁵ Constituent Assembly Debates, Vol VII, pp 1157 58

⁶⁶ जीप एव सयार मकानो का घाटाला सम्ब घी मामला पर इसी प्रकार आवरण डाला गया था ।

⁶⁷ Rao, K V Parliamentary Democracy in India pp 70 71

मारतीय सविधान में ब्रिटेन की मौति ही ससदीय प्रणाली है और मन्त्रिमण्डल, जिनम व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, ब्रिटिश मित्रमण्डल की मौति एक कडा एव वनसुआ है जो व्यवस्थापन अन को कायपालिका सं जोडता है मित्रमण्डल को व्यवस्थापिका के बहुमत का विश्वास प्राप्त होने के कारण दोना ही विधायी एवं कायपालक दायिता पर उसका नियात्रण हाता है। या त्रमण्डल के सदस्य चुकि मूल बातों में एकमत होते हैं और सामृहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर काय करते हैं अत नीति मन्य घी महत्व पूण प्रश्नों का वे ही निधारण करते हैं।

समोक्षा-मारतीय मित्रमण्डल भी हगलैण्ड की माति अभिसमय या विकास का परिणाम है। सविधान मित्र परिषद अर्थात काउसित ऑफ मिनिस्टम (Coun cil of Ministers) का विधान करता है। मन्त्र-परिषद (ministry) म समी प्रकार के मानी होते हैं। 'Cabinet' शब्द का प्रयोग सन्तियान में कही नहीं किया गुमा है। 1952 ई के प्रयम निर्वाचन के पश्चात प्रयम बार प्रधानम भी ए नेहरू ने 14 मि उ-मण्डलीय मित्रया की नियक्ति की थी।

यद्यपि मित्रमण्डल एक अतिरिक्त सर्वेधानिक विकास है परातु यह भारतीम मवधानिक प्रणाली का आधार है। यह सर्वोक्च नीति निर्देशक शक्ति है। यह नीति-निर्माता एव कामपालिका विभागों के बार्यों का सम वयकता एवं विधानमण्डल का माग-दशक ह । मित्रमण्डल का एक निकाय के रूप में अधिवेशन होता है। इगलण्ड की मौति मारत म भी मित-परिषद की कमी बठक नहीं होती और न वह नीति निर्माण ही करती है। अत मन्त्रिमण्डल एक वडे वृत्त (मित्र-परिपद) वे मीतर एक लघ वस है। यह शासन की चालक एवं निर्देशक शक्ति है।

मारतीय सविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 के द्वारा उत्तरदायी शासन की स्यापना की गयी है। परातु य साविधानिक उपवाध अपूर्ण हैं। एक प्रक्त अभिसमय एव परम्पराओ द्वारा निर्णीत किये जान के लिए रह यया है। यह कभी नहीं है अपित पण ही है। अभिसमयों के विकास के फलस्वरूप मित्रमण्डलीय कायपद्वति में अवसर एव परिस्थितियों के फलस्वरूप नमनीयता ही वायेगी।

भारतीय मित्रमण्डल की विशेषताएँ ब्रिटिश मित्रमण्डल के समान ही हैं। मामुहिन उत्तरदायित्व, गोपनीयता एव राजनीतिक एकरसता कसिद्धान्त पर मित्रमण्डेस आधारित है। मन्त्रिमण्डल कं अधिनेशन गुप्त होते हैं कायवाही भी गुप्त होती है, मभी सदस्या को मित्रमण्डल के अधिवेशन में अपने विचार व्यक्त करन की पूर्ण स्वत पता है परन्तू वे उसका सावजनिक रूप से उल्लंख नहीं कर सकत । प्रधानमन्त्रा मित्रमण्डल का नेता होता है और मित्रमण्डल का विधानमण्डत से घनिष्ट सम्बय होता है। पण्डित नहरू के प्रथम मित्रमण्डल म अनव स्वतात्र एव निन्तीय सदस्य

Rai Soheb Ram Jawya Kapur & Others v The State of Punjab, 1955, 2 SCR, pp 230 37

ये। व काग्रेस दल के सदस्य नहीं थे—जैसे श्री अग्येडकर, रुयामाग्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह, गोपालस्वामी आयगर एवं पणमुख चेट्टी। दश्च क विमाजन के तुरत्त बाद पुत्रिमाण के लिए इस प्रकार की व्यापक एक प्रकार स राष्ट्रीय सरकार, की राष्ट्रीय एकता हेतु आवश्यकता भी थी पर तु इसके पश्चात मित्रमण्डल म राज नीतिक एकस्पता निरत्तर पायी गयी हैं। 1962 ई के चीनी जाकमण के सकटपूण समय म मी भी नेहरू ने अनेक सुभावा के वावजूद भी मित्रमण्डल वो राष्ट्रीय सरकार का रूप प्रता नहीं किया था।

यह कहा जाता है कि योजना आयोग एव राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना स मित्रमण्डल की गत्तिया एव स्थिति पर प्रमाव पड़ा है। याजना आयोग की सुपर किविनेट, आर्थिय मित्रमण्डल कोदि की सना दी जाती है। यूत्यूव वित्त-सिंवत का यह कथन है कि योजना आयोग अत्यिषक सित्तियाली हो गया है तथा निर तर के द्रीय मित्रमण्डल के विपत्नो एव सित्तियों को अविक्रमण करता रहता है। शीए के च द्रा ने इसी मत का समयन करते हुए कहा था कि योजना आयोग की स्थिति मित्रमण्ड लीय व्यवस्था के अनुरूप नही है। आलोचका का यह भी मत है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के द्रीय मित्रमण्डल की सित्तिया का अवस्था कर रही है। परातु ये तक अविद्यायीत्तियुण है। राष्ट्रीय विवास परिषद के द्र एव राज्यों के मध्य विचार विभाव का एक जीरम मात्र है। योजना आयोग की कोइ सिविधक (statutory) या सब-धानिक स्थिति नहीं है। इसकी स्थापना कायपालिका के आदेश पर दुई है।

भारतीय प्रधानमन्त्री

प्रधानमंत्री मिनमण्डल का प्रधान तथा के ब्रीय झासन का प्रमुख है। सिद्धा त म मिन्रया की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है पर तु वास्तव म वे प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त किय जात हं। प्रधानमंत्री के चुनाव को राष्ट्रपति केवल स्वीकृति प्रधान करता है। मित्रया को परच्युत करने की छोक्त औ व्यवहारत प्रधानमंत्री म ही निहित है। सिव्या के अनुसार राष्ट्रपति का मित्रया को परच्युत करने का अधि-कार है पर्यु इस अधिकार का प्रयाग वह प्रधानमंत्री के परामय पर करता है। अत मित्रमण्डल के सदस्यों को नियुक्त एव पदच्युत करने के अधिकार प्रधानमंत्री का ही प्राप्त है। भारतीय प्रधानमंत्री विदेश प्रधानमंत्री की माति, खास्की के दाब्दों म, मित्रमण्डल के निर्माण, जीवन एव मस्तु के सम्ब द म के ब्रीय स्थित रखता है। वह मित्रमण्डल के निर्माण के अतिरिक्त उसक मदस्या से परिवतन भी कर सकता है। प्रधानमंत्री का त्यागपन मित्रमण्डल का त्यागपत्र होता है। वह सारसमा के विपटन की मौंग कर सकता है।

⁶⁹ श्रीमती इतिरा गाणी ने 1970 ई मं संखद के विघटन की माम की थी जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार किया था।

भारतीय प्रधानमन्त्री ससदीय प्रणाती का कृष्ट विष्टु एवं आधार स्तम्म है। हो अम्बदकर के अनुसार प्रधानमंत्री विश्वमण्डल स्पी महराव का आधार प्रजर है। किंद्रिस प्रधानमंत्री के सम्बन्ध यं कहे यव सभी क्यन बारतीय प्रधानमंत्री हर पूणस्पण लागू होते हैं।

प्रपानम भी की नियुक्ति

सविधान ने अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमात्री नी नियुक्ति की व्यवस्या है पर तु राष्ट्रपति लोगसमा म वहमत दल व नता वो प्रधानमन्त्री पद के लिए जाम ियत करता है। यह अभिसमय भारत म भी मा य है। विशव 24 वर्षों म भारतीय ससद म काँग्रेस दल रा बहुमत रहा है अत इस काल म काँग्रेस दल के नेता की ही प्रधानमंत्री नियक्त किया जाता रहा है। प जनाहरताल नहरू प्रथम, द्वितीय एवं ततीय निर्वाचनों के परचात प्रधानम भी बने ये। स्वत प्रता प्राप्ति के परचात वे देश के प्रधानमानी बने और मस्यपयन्त इस पद पर बने रह । जनके बाट भी लालबहाटर हास्त्री एव श्रीमती इदिरा गा भी त्रमस प्रभानम श्री वने । लोगसमा म स्पष्ट बह भारत भी अवस्था म प्रधानम में की निर्मुक्त म राष्ट्रपति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उसे अनिवायत बहुमत दस के नता नो प्रधानम मी नियुक्त करना पदता ह परन्तु तोकसमा में स्पष्ट बहुमत के अमाद म राष्ट्रपति को प्रधानम नी का अपनी इन्द्रानसार चयन का अवसर प्राप्त हो जाता है। सविधात इस सम्बंध में मौन है कि राष्ट्रपति लाकसमा के सदस्यों में से एवं लोकसमा के बहमन दल के नेता का ही प्रधानमात्री बनवा। लेक्नि सविधान के इस मीन का काई महत्व नहीं है। ब्रिटेन म 1923 ई के परचात सोकसमा के सदस्य एव नेता को ही प्रधानमानी नियुक्त करने की परम्परा स्थापित हइ है। यह लाकत नीय मिद्धात के अधिक अनुरूप ही है। मारत में हम इसी परम्परा को मा यता देनी चाहिए। क्या किसी एस व्यक्ति का जो लोकसमा का सदस्य न हो प्रधानमात्री नियुक्त किया जाय ? क्या यह उचित होगा ? न्या यह ससदीय प्रणाली के अनुरूप हु ? यद्यपि राज्या म मुख्यम त्री के पद पर उच्च सदन के मनोतीत सदस्यो एव ऐसे व्यक्तियो को मुस्यवानी बनाया गया है जो कि विधानमण्डल के किमी भी सदन के नदस्य नहीं ये लेकिन यह स्वस्य परम्परा नहीं है। अत प्रधानमन्त्री के स दभ में इस असोकता ितक परम्परा का अनुवसन नहीं होता चाहिए। किसी ऐमे व्यक्ति की जो जनता का प्रतिनिधि न हो, प्रधानम नी नियक्त करना उचित नहीं हामा और न सविधान की एसी इच्छा ही है।

^{70 &#}x27;The Prime Minister is really the Leystone of the arch of cabi net'.—Dr B R Ambedlar Constituent Assembly Debates, p 1159 मनरबीय है, ताब मोर्स ने बिटिश प्रधानम त्री के सम्बर्ध म यही मन बस्क किया है।

प्रधानम त्री के काय एव दायित्व

प्रधानमानी को ब्यापक शक्तिया एव दायित्व प्राप्त हैं। ब्रिटिश प्रधानमानी को कभी कभी एक तानाश्चाह की सना दो जाती है। उदाहरणार्थ, ग्रीब्स का कपन है कि प्रधानमानी की औपचारिक शक्तिया निरकुश शासक से मिलती है।⁷¹

बहु शासन का निर्माण करता है। मिनाण्डल के सदस्यों का नुनाव करता है। मिनाण्डल के आकार को निश्चित करता है। प्रधानमानी मिनाण्डल के सदस्यों के चयन में स्वतान नहीं होता—उस पर अनेक व्यावहारिक प्रतिवाध होते हैं। प्रवाहताल नेहरू जैस व्यक्ति को भी अपने मिनाण्डल के सदस्या के चयन में स्वतान नहीं होता—उस पर अनेक व्यावहारिक प्रतिवाध होते हैं। प्रवास को सहस्य के के बातों का व्याव रखता पंडा पान पान पान करता, प्रशासनिक कुरावता, समसा अनेक वातों का व्याव रखता पंडा वातीय एवं अस्पर्वका के प्रतिनिधित्य को सदैव व्यान ने रखना पडता है। प्रवास ती को वस के विर्वेद व्याव में रखना पडता है। प्रवास मिनाण्डल के कुछ सदस्या को मिनाण्डल में अनिवासन कामिल करना पडता है। पुराने मिनाण्डल के कुछ सदस्य रहे हैं। श्री जगजीवनराम 1947 ई से के द्वीय मिनाण्डल के सदस्य रहे हैं। श्री जगजीवनराम 1947 ई से के द्वीय मिनाण्डल के सदस्य हैं। विभागों का वितरण मी भारतीय प्रधानमानी हो करता है पर तु उसे विरिव्द एवं प्रभावशाली सहयोगिया की स्वित को ध्यान में रख कर ही विभागों का वितरण करना पडता है। श्री वल्लमभाई पटेल एवं मारारजी दीस कर ही विभागों का वितरण करना पडता है। श्री वल्लमभाई पटेल एवं मारारजी दीस कर वाह तिवाल ने हरू एवं थी लालबहातुर बाहरी न कमस्य अपने मिनाण्डल में जप प्रधानमानी का पद प्रवान किया था।

प्रधानमंत्री मित्रमण्डल की बैठका की अध्यक्षता करता है। वह मित्रमण्डल की अधिकाश समितिया की भी अध्यक्षता करता है। यित्रमण्डल के विचाराथ प्रस्तुत किये याने वाल मामला को तय करता है। प्रत्येक मत्त्री किसी प्रस्ताव का मित्रमण्डल के विचाराय उपस्थित करता है। प्रत्येक मत्त्री है। वह विमिन्न यिमागा के कार्यों में समय्य स्थापित करता है। शासन के विमिन्न यामें का वह निरीक्षण करता है। मित्रमण्डल के हर कार्य के लिए अन्तत प्रधानमन्त्री ही उत्तरदायी हाला है।

प्रधानमंत्री लाक्सना का तेता होता है। इंगलण्ड म प्रधानमंत्री इम वासिदर को किसी अप मात्री को भी भीष सकता है। वेदिन उत्तरपाधित्व प्रधानमंत्री का हो रहता है। ससद म वह जासन का प्रमुख बस्ता हाता है। प्रदेवन विनाग क सत्या म व उसका मन पासन का मत माना जाता है। थी कुटणमेनन के अनुमार, प नेहर जब ठीक एवं उचित समन्ति ये विभिन्न विनागा के बार में मनद म स्पन्नीरण हुत हस्त-क्षेत्र करते थे। कभी-कभी इमन सम्बन्धित संत्रिया वा दुविया नी होती थी। व

^{71 &}quot;The formal powers of the Prime Minister of England resemble closely those of an autocrat '-Greaves The British Constitute 1951, p 74

विरोधी दल रे प्रति याय री भावता स प्रेरित होकर अधिक शहरण है। वर्त थे। जब वे समभते थे कि प्रस्ता का मन्तीयजनक उत्तर नहीं दिया जा रहा है ने स्वय अपने सहयोगिया से पुछ जान बाले प्रकों का उत्तर दन समृत थे।

प्रधानमात्री राष्ट्रपति एव मत्त्रिमण्डल ने साव्य कही है। वह मित्रमण्डल के सभी निणमों से राष्ट्रपति को मुचित रराता है, एव उस विधि प्रस्तावा की मुचित होता है। राष्ट्रपति हारा मौगी मोगी सुचनाओं एव विधि प्रस्तावा को वह उसके विधारप प्रस्तुत करता है। विधारण प्रस्तुत करते की मौग का प्रधानमात्री ही क्यांवित करता है। की मौग सामा प्रधानमात्री की अनुमति के नोई मुचना प्रेषित नहीं कर सकता। प्रधानमात्री को अनुमति के नोई मुचना प्रेषित नहीं कर सकता। प्रधानमात्री राष्ट्रपति का सर्वोच्च सताहकार होता है।

वह शासन के महत्वपूष पदा---राज्यपाल मंत्री राजदूती, वाणिज्य दूती,

मित्रयो, विभिन्न आयोगा व अध्यक्षो एव सदस्या को नियुक्त करता है।

वह विदेश नीति का निमाता होता है। युद्ध एवं शांति सम्बंधी मामला में उसका निषय अतिम होता है। अत्तर्राष्ट्रीय सम्मेलना में वह देश का प्रतिनिधित्य करता है।

स्थिति

प्रधानमंत्री का पद सर्वोच्च है। वह समक्का म प्रधम होता है। प जवाहर लाल नेहरू एवं श्रीमती इिंदरा या थी तो अपने मित्रमण्डल के नता ही नहीं अपितु स्वामी हैं। मित्रमण्डल में उसकी दिवार मुख एवं प्रधान हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्र का नेता एवं मानवरक होता है। वह देरा की राजनीति का सुवधार है। विश्व ने सम्बन्ध का नेता एवं मानवरक होता है। वह देरा की राजनीति का सुवधार है। विश्व ने स्वचानक होति है। उसके सामा प्रविद्या प्रधानमंत्री के ही निर्वाचन होते हैं। विश्व चुनावों म एक ही नारा था काप्रस को वाट देकर नेहरू के हाथ मजबूत कीजिए। अब मारतीय राख नीति म सारा बक्र प्रधानमंत्री के ही निर्वाचन होते हैं। विश्व चुनावों म एक ही नारा था काप्रस को वाट देकर नेहरू के हाथ मजबूत कीजिए। अब मारतीय राख नीति म सारा बक्र प्रधानमंत्री श्रीमती इिंदरा मां के चारों आर पूमता है प्रधानमंत्री श्रीमती इिंदरा मां में एक होते दे प्रधानकां ने हैं। प्रधानमंत्रमंत्री की स्वित उसके व्यक्तित पर निमर करती है। प जवाहरकाल नेहरू का प्रधावशाल व्यक्तित था। देश की राजनीति म जनां प्रधा स्थान था एक व्यवस्थ वा । देश की राजनीति म जनां प्रधा स्वाचा था एक व्यवस्थ वा । देश की राजनीति म जनां प्रधा स्वाच वा वा स्वच्य वा । स्वाच कर उनने परिधा था। वह पत्र दारावक ने एकक्षत्र नेता थे। सीमती इिंदरा गां भी की मेरी दिखिलत है।

प जवाहरताल नहरू एवं डिंदरा या थी के मध्य के काल म प्रथानम त्री

की स्थिति कुछ धूमिल पड गयी थी। परत् 1965 ई मे भारत पान युद्ध के परः प्रधानम त्री सालबहादुर शास्त्री की प्रतिष्ठा जब अपनी चरम सीमा पर थी र उनका निधन हो गया था।

मारतीय राजनीति थे प्रधानम नी सपूरण घासनत न पर छाया रहता है। कि दीय मित्रमण्डल का प्रधान तो है ही जिन राज्यों में काग्रेसी मित्रमण्होंते हैं उनका भी बह अतिय घासरण होता है। दलीय व्यवस्था के माध्यम से बहु पर निया नण रखता है। अनेक राज्यों के मुरदमा नियों की नियुक्ति में उसका नि अविता नहां है। पर विश्वकर शुक्त की मन्यु के पश्चात को कैलाशनाय काटजू प्रधानम नी का विश्वासपान होने के कारण ही भष्य प्रदेश के मुरदम नी पर पर पह इंड किया मया था। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। यही नहीं, राज्या के मित्रमण्डला की हं भी हाई कमाण्ड के परामश्च से ही तय होती है। स्मरणीय है प्रधानम नी की दल शीप पर के प्रीय स्थित है।

कई मिं तमण्डलीय सदस्यों को प्रधानमं त्री से असहसत होने के कारण अपने से हटना पड़ा है। भूतपूर्व वित्तमंत्री श्री सी दी देशमुख ने मापा सम्बंधी विश्व के समय कहा था कि वस्वई के प्रकल पर मिं तमण्डल ने कोई निषय नहीं लिया है समय कहा था कि वस्वई के प्रकल पर मिं तमण्डल ने कोई निषय नहीं लिया है है। अधिवर में भी कुछ हूँ। ये मारत वर प्रधानमंत्री हूँ एव प्रधानमंत्री प्रधानमं है। आखित में भी कुछ हूँ। ये मारत वर प्रधानमंत्री हैं एव प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री हैं। में यह समकता हूँ कि प्रधानमंत्री कं क्या कतव्य है। यह कहना कि प्रधानमंत्री के दिस संवत्य नहीं दे सकता स्वय एक जैतानी वक्तव्य है। यह कहना कि प्रधानमंत्री सदम मंत्री के वह स्वय है जिलके चारा तरफ अनक्षण भूमत हैं। प्रधानमंत्री के नियुक्ति एव प्रबन्ध संवत्य दी शक्ति हो। उपधानकंत्र के स्वय के अवस्त के उपलब्ध सम्मव है। कि मंत्री के कार के सव्य माम सामूहिक उत्तरदायित्व के आदत्त की उत्तरिवार के विद्व विद्री हं रमत्री के दाजनीतिक जीवन के अत्त के लिए उत्तरदायी हो सकता है।

प्रधानमानी श्री नेहरू की शक्ति का कारण उनको व्यक्तिस्य था। वे स्वय र संस्था थे एवं दल तथा ज्ञासन पर उनका एकदान राज्य था। वे प्रमुख राष्ट्रीय नेर प्रवत दलीय सगठनकर्ता तथा लोकप्रिय जननायक थे। ऐसे सशक्त व्यक्तिएव के प्रधा माने होने के कारण उस पर को व्यरिभित प्रसिष्ठा एवं मरिसा प्राप्त हुई है। वेकिन प्रधानमानी निर्मुख नहीं हो सकता। श्री जल्लादी क्रण्यासामी अध्य

का इस सम्बन्ध में कबत है कि "इसने कुछ सत्य हो सकता है कि प्रधानमा अध्य का इस सम्बन्ध में कबत है कि "इसने कुछ सत्य हो सकता है कि प्रधानमा भी नि कुछ हो सकता है। (लेकिन) यह तभी सम्मव है जबकि उसको चुनने वाली ससद ह दल दोनो ही निष्क्रिय हो जायें।" ⁸ फिर आगामी निर्वाचनो हम मय, दल के अलोव

⁷³ Lok Sabha Debates, July 30th, 1956 74 Sir A Krishnaswami Ayyer Constituent Assembly P

त्रिम हो जाने की सम्मायना तथा यत्तत नीतिया के फास्यरूप दत म ही प्रतिदृत्तिया हारा विद्रोह प्रधानमंत्री वर प्रचानद्वाली नियंत्रण के रूप म काम करते हैं। इसर म प्रधानमंत्री हो सरकार है यह बाजरिक एवं विद्राह नीति का निर्माता है। प्रिष्ट प्रधानमंत्री की भौति वह दल एवं शामन का अध्यक्ष होता है। युद्ध-काल म उसकी सिक्ति अधिक व्यापक हो जानी है। श्री एवं थी पाडगित्त का कथन है कि प्रधानमंत्री पो व्यापक सांतियों प्रधान हैं और पादि वह स्वयं लीकता नीम प्रकृति का व्यक्ति नहीं है। यदि तहरू के स्थान पर भोई कमकोर व्यक्तित्र का ब्यक्ति होता होता तो सम्मवत राष्ट्र पर भोई कमकोर व्यक्तिरूव का ब्यक्ति प्रथम प्रधानमंत्री हुता होता तो सम्मवत राष्ट्र पति के प्रभाव म आकर उसकी विद्याल हो वाने वी होती।

भारतीय सद्य मे राउपपाल

भारतीय संघ के प्रश्निक राज्य म राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। 15 वह वायपालिका का प्रमुख है एव राज्य को नायपालिका को प्रमुख है एव राज्य को नायपालिका को प्रमुख है एव राज्य को नायपालिका को का न्वय या अपने अधी तस्य अधिकारियों के माध्यम सं किया विद्य करता है। "राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है एवं उसी के प्रमाद पव त नह प्रार्ट्स रहता है।" यदाय उत्तका सामाय पायकाल 5 वय है। प्रारम्भ म सिवधान समा निविधित राज्यपाल के रक्ष से थी। पर तु उसकी तीव आलोचना हुई की। राज्यपार एवं मित्रमांवत राज्यपाल के रक्ष से थी। पर तु उसकी तीव आलोचना हुई की। राज्यपार एवं मित्रमांवत उत्तक हो नी तिवधित होने की अवस्था में सब्धानिक मित्रपेंव की हुर सम्मावता उत्पन्त हो जाती है। राज्यपाल के एवं पर वही ध्वतिक नियुक्त किया जा सकता है जो कि मारतीय नाग रिक्त हा तथा 35 वयं की आयु पूर्ण कर चुका हो। "राज्यपाल को किसी राज्य विधान मण्डल या समय के होगा सदनों में किसी सदन का मी सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि काई ध्यक्ति किसी राज्य के विधानमण्डल या भारतीय ससर का सदस्य होता है तो वह राज्यपाल के यद को ग्रहण करन की तिथि से स्वत हो इन पन। से हुट बाता है। "राज्यपाल का यद को ग्रहण करन की तिथि से स्वत हो कम वनर से हुट बाता है। "राज्यपाल का एत्रक कार्यों के लिए किसी यागालय के समस उत्तरसाथी नही ठहराया जा सकता और उसकी पदाविध काल म उसके विकद्ध कोई फीजनारी पुन्दस्य नहीं हुटा सा

⁷⁵ सातने सर्वभानिक संबोधन (1956) द्वारा अनु 153 के अधीन आवश्यक्ता पड़न पर दो या जीवक राज्या के लिए एक ही राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। श्री निष्णु सहाय असम व नायालक दोनों के अवनर है। एक ही राज्यपाल होते हुए भी राज्य पुशक विधिक इंकाइयाँ होती हैं।

⁷⁶ अनुष्ठेद 154—समुक्त राज्य अमेरिका म राज्यपात अत्यक्ष रीति से जनता हारा चुना जाना है और राज्य विधानमण्डल हारा महासियोग नगाकर हटाया जा सकता है।

⁷⁷ अनुच्छेद 155 एव 156।

⁷⁸ अनुष्येद 153।

⁷⁹ वनुष्हेद 158 (

चताया जा सकता । उसे ब दो भी नही वनाया जा सकता । व्यक्तिगत रूप से राज्य-पाल पर दीवानी कदालत मे नोई मुकदमा दो माह पूच नोटिस देने के परचात ही दायर किया जा सकता है ।

राज्यपाल की निगुक्ति के सम्ब प मे दा स्वस्य परम्पराओं का विकास हुआ है। सामायत दूसरे राज्यों के निवासी को ही किसी राज्य का राज्यपाल निगुक्त किया जाता है। इसके केबल दो अपवाद हैं। डॉ एच सी मुलर्जी को पिहनमी बगाल का राज्यपाल तथा मैसूर के महाराजा को मैसूर (वतमान कर्नाटक राज्य) का राज्य पाल निगुक्त किया गया था। सामायत सोकसाम के सदस्य, पदिनृत्त यायाधीश जनरल एव राजनीतिण राज्यपाल निगुक्त किया जाते रहे हैं। राज्यपाल के पद पर सत्ताक्ष्य कर एक सोकसाम के सदस्य, पदिनृत्त यायाधीश जनरल एव राजनीतिण राज्यपाल निगुक्त किया जाते रहे हैं। राज्यपाल के पद पर सत्ताक्ष्य हम से पर पर सत्ताक्ष्य स्व से या सावजनिक जीवन से लोकप्रियता खी चुके थे। अत राज्यपाल का पद सत्ताक्ष्य इल के ऐसे नेताओं के लिए आध्य स्थल वन गया है।

काय एव शवितया

राज्यपाल को निम्नलिखित शक्तिया प्राप्त है

कायपालक शिक्तवा—सिंधान के अनुसार राज्य के सभी कायपालिका सम्बाधी काय राज्यवाल के नाम पर सम्मादित किये जाते हैं। ⁶⁰ राज्यपाल को मुख्य मानी की अध्यक्षता मानी परिपद निमुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। मिन परि पद का काय राज्यपाल को स्थिविकीय कार्यों के अधिरिक्त अप कार्यों में सहयोग में सहायता देना है। स्विविकीय कार्यों के सम्बच्ध में राज्यपाल का निषय अस्तिम होता है एव तत्सन्य भी निणय को किसी पायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मिन-परिपद हारा दिया गया परामत पुत्त होता है और कोई पायालय उसकी जाज नहीं कर सकता। ⁸¹ सिद्धान मं मिन परिपद राज्यपाल के प्रसाद-पद न प्रसन्ध रहती है पर चुनौती में मिनमण्डल राज्य विधानमण्डल के निम्न सदन—विधानसमा—के प्रति उत्तरायों होता है और उसी के प्रसाद प्रन्य प्रवादय रहता है।

पुरुषम नो का यह कतव्य है कि वह भनि-यिएव के राज्य प्रशासन एवं विधि प्रस्तावों सम्बन्धी समस्त निष्यों की सूचना राज्यपाल को दे। विश्व आवश्यक होने पर राज्यपाल क्षय किसी भी मूचना की मान गुरुषम नी से कर सकता है। राज्यपाल मनि परिषय के किसी खस्स के निष्य को मनि परिषय के समझ विचाराय प्रस्तुत करने का निर्वेश गुरूष मनी को दे सकता है। विश्व आज प्रदेश एव प्रजाब मे

⁸⁰ अनुच्छेद 156 (1)

⁸¹ अनुच्छेद 163 (1)

⁸² अनुच्छेद 167 (अ)

⁸³ अनुच्छेद 167 (स)

640 | नापुत्तिक शासनतात्र

रोत्रीय समितियाँ हैं। उनके परामस को सामन एवं विधानमण्डल द्वारा सामान्य स्वीनार विधान बाता है पर जु दौना—समिति एवं सासन तथा विधानमण्डल—मं विवाद भी स्विति में राज्यपाल का विणय अतियम होता है। में महाराष्ट्र एवं पुत्रपत के राज्यपाता को मी राज्य के सभी भाषा म समान आर्थिक एवं यसिक विस्तर के राज्यपता वो भी राज्य के सभी भाषा म समान आर्थिक एवं यसिक विस्तर के राज्यपता वो मी पाय स्वीत यहाँ। समरन दो के अनुगार, विशेष नाधिवते के सम्या दन म राज्यपता को मीच परिषद की सलाह स स्वता म रहकर काय करने का अधिकार है। है

ज्बन यायालया के यायाभीशा की नियुक्ति राज्यसल द्वारा नहां की आती है परन्तु राष्ट्रपति द्वारा यायाभीशो की नियुक्ति विचे जाने के पूब उससे प्रामय अववय सिया जाता है। 18 राज्य के सहायिवका एव राज्य तीक हेवा आयोग के सहस्यों को वह नियुक्त करता है। 18 गामन एव राज्य के कार्यों के सुस्रवालन के लिए नियमादि यनाने का ज्ये अधिकार प्राप्त है।

विधान में विज्ञ जान्य निर्माण के विधानमण्डल का अिमन अग है। विधानमण्डल को आहुत । यह दियाल करने का उसे अधिकार है पर जु विधानमण्डल के दो अधिकार के मध्य 6 माह स अधिक अदार नहीं होना चाहिए। यह विधान समा को विधिद्ध कर सबता है एवं एक सदन या दाना सदनों की विम्मित्त बैठक में भापण प सकता है। विधानमण्डल के विचाराय प्रस्तुत विधेयका के सम्बन्ध में भापण प सकता है। विधानमण्डल के विचाराय प्रस्तुत विधेयका के सम्बन्ध में भापण प सकता है। वह सामा या निर्वाचन के परवाद विधानमण्डल के प्रथम अधिकार एवं वर्ष के प्रथम अधिकार में भापण पता है। विधानमण्डल हारा पारित विधेयनों को राज्यपाल को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। वह विधेयक कर सकता है या उसे राज्यपित की विचाराय प्रयित कर सकता है। यन विधेयकों में अधिरिक्त कर सकता है। यन विधेयकों से वह सदन या सदनों को स्वाच मा साधीभन सहित विचाराय लीटा सकता है। विधानमण्डल के सामावसान काल में राज्यपाल का अध्योदेश आरी रखने का अधिवान हार के शिवानमण्डल का अध्योदेश का अधुवान प्रारम्भ होने के 6 सताह के भीदर यदि विधानमण्डल हारा अध्योदेश का अनुसादन प्रारम्भ होने के 6 सताह के भीदर यदि विधानमण्डल हारा अध्योदेश का अनुसादन

⁸⁴ अनुच्छेद 371

⁸⁵ Amarnanda The Constitution of India, 1962 p 198

⁸⁶ अनुच्छेद 217 (1)

⁸⁷ अनुच्छेद 216 (1)

⁸⁸ अनुच्छेद 174

⁸⁹ अनुच्छेद 175

⁹⁰ अनुच्छेद 176

⁹¹ अनुच्छेद 213

नहीं किया जाता तो वे स्वत ही निष्प्रमावी हो जाते है। यदि अध्यादेशा की विधान मण्डल अस्वीकृत कर देता है तो व समाप्त हो जाते है। परात राज्यपाल राष्ट्र पति की स्वीकृति के बिना ऐसे किसी अध्यादेश को जारी नहीं कर सकता जिससे सम्बन्धित विधेयक पर विधानमण्डल मे प्रस्तुत करने के प्रव राप्ट्रपति की स्वीकृति अनिवाय हो या राज्यपाल ने सम्बाधित उपबाधा विषयक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रोक रखा हो या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रोके गये उन उपबाधी सम्बाधी राज्य विधानमण्डल के विधेयक की राप्ट्पति द्वारा स्वीकृत कर दिया गया हो ।

विसीय शक्तियाँ-कोई धन या वित्त विधेयक या वित्तीय मामला म सशोधन सम्ब धी विधेयक राज्यपाल की अनुमति के अभाव म राज्य विधानमण्डल म प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । परन्तु किसी कर को कम या समाप्त करने वाले विधेयक पर राज्यपान को एसी किसी सस्तुति की आवश्यकता नही है। राज्यपाल का दायित्व यह देखना भी है कि प्रत्येक वित्तीय वष के आय व्यय विवरण को विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। " सभी प्रकार की अनुदान की माँगे, चाहे वे पूरक, अतिरिक्त अयवा बढी हुई अनुदान सम्बाधी मागे ही नया न हा, राज्यपाल की सस्तुति पर ही विधानमण्डल म प्रस्तुत की जा सकती है। 93

पाधिक शक्तियाँ--राज्यपाल को राज्य विधि सम्बन्धी अपराधी के लिए दण्ड को कम, स्थिगत या क्षमा करने के अधिकार प्राप्त है। " बम्बई उच्च याया-लय के अनुमार राज्यपाल की यह शक्ति प्रकृति एव प्रमाव म ब्रिटिश काउन था अमे रिकी राष्ट्रपति की शक्ति के समान ही है। राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग, मुकदम के दौरान या समाप्ति पर कर सक्ता है, पर तु उसे निरकुख दग से इसका प्रयोग नही करना चाहिए 1⁹⁵

अ य शनितयां--लोक सेवा आयोग अपने काय का वार्षिक प्रतिवेदन एव महालेखा परीक्षक द्वारा जाय व्यय के लेख परीक्षण सम्बंधी प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है जो उह मित्र परिपद को भेज देता है। प्रतिवेदना पर मित परिपद की टिप्पणियाँ प्राप्त होने पर राज्यपाल उन्ह विधानसमा के अध्यक्ष को विधानमण्डल म प्रस्तत करन के लिए भेज देता है।

स्थिति

राज्यपाल को सवधानिक स्थित --राज्यपाल की दोहरी स्थिति है । एक

⁹² अनुच्छेद 202

⁹³ अनुच्छेद 205

⁹⁴ अनुच्छेद 161

⁹⁵ नानावती विवाद म बम्बई उच्च "यायालय वे निणय पर आधारित ।

तरफ तो वह राज्य का सबैधानिक अध्यक्ष है तो दूसरी तरफ वह कंद्र का प्रतिनिधि या अभिकर्ता है। सामा य काल में राज्यपाल राज्य के सबैधानिक अध्यक्ष के रूप म काय करता है। राज्यों मं भी केंद्र की तरह ससदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गरी है। 'सहायता एव परामञ' (Aid and Advice) शब्दो का अथ यह है कि राज्यपात मित-परिषद के परामर्शानुसार काय करेगा । पर त स्वविवेकीय मामलो के सम्बन्ध मे वह स्वतात्र है । सविधान द्वारा स्वविवेकीय वास्तियों की कोई परिमापा प्रस्तत नहीं की गयी है। राज्यपाल का निवेक ही अतिम निर्णायक है। दो प्रावधान इसका अप बाद है। वे सामा य महत्व के है। प्रथम, असम के राज्यवान की राष्ट्रवित के अपि कर्ता के रूप में सीमान्त क्षेत्र के प्रशासन का अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त असम सरकार एव जन-जाति क्षेत्र की जिला परिपद के मध्य खटान गाँगल्टी सम्बाधी विवाद का निणय राज्यपाल स्वविवेक से करता है। दितीय, राष्ट्रपति द्वारा जब किसी राज्यपाल को अधीनस्य के द्र प्रशासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त किया जाता है ती राज्यपाल राज्यपति के अमिकतों के रूप में काय करता है और उसका निणय अतिम रिवाही । श्री हुमीदास नमु कं जनुकार, 'बृश्चि स्विधिवरीय राक्ति असस के राज्यपान को केवल दो सामा मामामा ने प्राप्ता है जल सविधान में 'स्विबिवेक से काय करते' बाबदो का उल्लेख एक सीमा तक मम्पादन का ही दोप है। '⁹⁸ अत राज्यपाल को मित परिषद के परामधा पर ही काम करना चाहिए। यापालम के अनुसार राज्यपाल बिना अपने मित्रयों के परामश के काय कर ही नहीं सकता^श और तस्सम्बंधी अमि ममयो का भी विकास हजा है।

राज्यपाल एव केन्द्र----राज्य की राजनीतिक स्थित एसी हो सकती है जयिक राज्यपाल के लिए मिनमण्डल की लालह मानना सम्मव ही न हा। यदि राज्य का सासन सविधान के अनुसार नहीं चलता है या मुख्यम भी का विधानमण्डल के बहुक्त का विद्यानमण्डल के के बहुक्त का विद्यानमण्डल के बहुक्त का विद्यानमण्डल के के सम्बय में का विद्यानमण्डल हो है या मुख्यम भी की प्राप्त वहुमत के समयन के सम्बय में में विद्यान की सम्बय करता है कि ऐसी स्थित का राज्यपाल को क्या करना चाहिए। यदि राज्य मिन परिपद ऐसी कोई विधि पारित करना पानमक्त पराने पर बल देता है जिससे सविधान का उल्लंधन होता है तो क्या राज्यपान के लिए मिन परिपद के ऐसे परामग्र को सानना आवस्थम है ? कुछ परिस्पतियों एसी हो सनती है जयित वह राज्यपात को सानना आवस्थम है ? कुछ परिस्पतियों एसी हो सनती है जयित वह राज्यपात को सानना करना चाहिए? अत राज्यपाल की स्थातिवार पराम परा में नेहरू न करा था कि निवंधित सान्य परान मनीनीत राज्यपाल को अपेक्षा प्रवचनावादों (एव) प्रान्तीयता को माननावा में भी नेहरू न करा था कि निवंधित राज्य

⁹⁶ Basu, D D Commentary on the Constitution of India, Vol 19, p 475 97 मुलीलनुमार बास बनाम पश्चिमी बगाल न गुरुव सहित्व ।

बतावा देने वाला हो सकता है ऐसी स्थिति म केंद्र के उसके साथ कम सम्बंध होंगे। ⁹⁸ अत राज्यपाल से केन्द्र के अभिकर्ता या प्रतिनिधि के रूप म महत्वपूरण भूमिका निमाने की आशा की गयी है। सवधानिक असफलता की स्थिति म उसे स्व-.. विदेक से काय करने का अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में मित-परिषद से परामश करता उसके लिए आवश्यक नही है। तब वह केंद्र का अभिकर्ता होता है तथा सबैधानिक विफलता सम्बाधी जो प्रतिवेदन वह के इको प्रस्तुत करता है उसे गुप्त रखना उसका कतव्य है। तत्पश्चात के इ के निर्देश के अनुसार ही उसे आचरण करना चाहिए। लेकिन जब तक राज्य मे सविधान के अनुसार सामा य स्थित बनी रहती है तब तक वह विशुद्ध सवधानिक अध्यक्ष है और उस अवस्था म मिन्न-रियद का परामश मानना उसका कतव्य है। सविधान समा के सदस्यों के राज्यपाल तथा के द्रीय शासन के सम्ब धो पर परस्पर विरोधी मत थे। भी टी टी कृष्णमाचारी जिनके मत से डॉ अम्बेडकर सहमत ये का कथन था कि 'मैं इन समस्त विचारो का खण्डन करता हूँ कि इस सदन के सदस्य मनोनीत गवनर को राप्टपति का अभिकर्ता बनाना चाहते हैं।"" परत डॉ अम्बेडकर ने बाद म एक प्रदर्न का उत्तर देते हुए अपने पूद मत का खण्डन करते हुए कहा था कि "प्रा तीय शासनों को के दीय शासन के अधीन काय करना चाहिए। फलत राज्यपाल को कुछ बातें राष्ट्रपति के विचाराथ रोकनी पडेगी जिससे कि यह पता चल सके कि प्रातीय शासन को जिन नियमा के अधीन काय करना है वे सर्विधान या के द्रीय शासन की अधीनता म हैं और उनका पालन हो रहा है।100 श्री महावीर त्यागी का मत इसी से मिलता-जुलता है। उनका कथन था कि राज्यपाल ने द्र का अभिकर्ता या माध्यम है जिसके द्वारा के दीय नीति को लागु किया जायेगा या रक्षा की जायेगी। राज्यपाल को एक ओर के द्रीय नीति के सरक्षक, तो इसरी ओर सविधान के सरक्षक के रूप मे काय करना चाहिए।101

क्यवहार से गवनर का बद— एउपपाल के पद पर अधिकासत सत्ताकड दल हारा अपने ही दल के व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है। विमिन्न राज्यपालों के अपने कामकाल सन्वाधी भिन्न भिन्न अनुभव है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थी एवं पी मोदी की अपने कामकाल सन्वाधी भन्न मिन्न बतुम्बर है। वे विमानीय सन्विधों एवं मुख्य सिवंद से सीया सम्पन्न पत्त के वे। तत्कालीय मुख्यम त्री श्री गोविंद वत्तरम पत्त को सहस्त मोद आपति मही था। श्री श्रीमकाध (जो लगातार 12 वर्षों तक तीन राज्यों से राज्यपाल पद पर रहे) का क्यन है कि वे सदव सवैधानिक अध्यक्ष के रूप में काम करते रहे हैं। श्री वी वी तिरि उत्तर प्रदेश मं राज्य-

⁹⁸ Constituent Assembly Debates, Vol VIII p 455

¹⁰⁰ Ibid , p 502

¹⁰¹ Ibid, pp 494 95

सविधान का रक्षक है।

दने का अधिकार प्राप्त है।

पाल थे। उस समय श्री सम्पूर्णान द जी मुख्यम त्री थे। श्री विरिका कथन था राज्यपाल सुसुप्त सहयोगी नहीं है। वह ठीक प्रवार से तभी काय कर सकता है म कि वह दूसरो पर हावी हुए विना गलतियों को रोके। श्री वी पी मेनन के अनुसा राज्यपाल की स्थिति नाममात्र के अध्यक्ष जैसी है। श्री वाटस्कर के अनुसार गर्म

दो तीन अवसरो पर गवनर के आचरणो की तीव निदा हुई थी एव वे ती विवाद का विषय वन गये थे। फलस्वरूप राज्यपाल के पद तक का समाप्त नरन क बात की गयी। 1959 ई म केरल शिक्षा विधेयक के विरोध में राज्यध्यापी आनी लन चला था। राज्य मे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। यह आदील माम्यवादी शासन के विरुद्ध हुआ था। राज्यपाल ने मित्रमण्डल के परामधा के दिना है मबैधातिक शासन की विफलता की घोषणा की थी फलत राय्ट्रपति शासन लागू क दिया गया । कुछ ने राज्यपाल के इस काय को असवैधानिक उहराया तो दूसरा है इस उचित बताया था । स्मरणीय है कि केरल की नम्बूदरीपाद की सरकार की विधान समा के बहमत का समधन प्राप्त था। एसी न्यिति में राज्यपाल को राज्य-मित्र मण्डल के परामध के बिना राष्ट्रपति को प्रतिवेदन नहीं देना चाहिए था। करल के साम्यवादी शासन के मतानुसार राज्यपाल को मिनमण्डल के परामश से ही प्रतिवेदन

दुमरा विवाद पहिचमी बगाल सं सम्बन्धित है। श्री अजय मुकर्जी की सरकार राज्य म व्याप्त अराजकता को रोकने म असमय थी। राज्यपाल थी धमवीर ने मूहव-मात्री की शीझ ही विधान समा को आहत करके अपना बहुमत प्रमाणित करने का निर्देश दिया था । लेकिन मुख्यम त्री न राज्यपाल द्वारा प्रस्ताविन तिथि के कुछ दिन पश्चात विधानसभा का सत्र आहुत करने का निश्चय किया था । इस पर राज्यपाल ने विधानसभा एवं मी त्रमण्डल दोनों को भग कर दिया और राज्य म शब्दपति शासन लाग कर दिया गया।

भेजना चाहिए था जबकि केंद्र का मत था कि राज्यपाल को स्वतात्र रूप से जापन

अत यह स्पष्ट है कि राज्यपाल की स्थिति एव उसकी शक्ति से सम्बर्धित कई बातें विवादास्पद हैं। उनम से मुख्य निम्नवत हैं

(1) राज्यपाल एव मन्त्रिमण्डल के सम्ब ध-नया राज्यपाल मुख्यम त्री क चुनाव म स्वतंत्र है? नगा मुख्यमंत्री का वह स्वविवेशानुमार पदच्युत कर सकता है ?

(2) शाज्यपाल एव व्यवस्थापिका के सम्बाध-नया गाज्यपाल को विधान समा को विषटित एव बाहूत करने सम्बाधी "सिजा प्राप्त हैं ? किन स्थितिया म वह उनना प्रयोग स्वविवनानुसार कर महता है ?

(3) सबपानिक असफतता की अवस्था में राज्यपाल की स्थित बया है ?

साराश-केंद्र व राज्यों म एक ही दल काँग्रेस के दीघकाल तक पदारूढ रहने के बारण राज्यपाल का पद परोक्ष म पड गया है। के द्रीय मित्रया एव राज्या के मित्रया म सीधे सम्पक स्थापित हा गय हैं। चतुय निर्वाचन के पश्चात स्थिति मे कुछ परिवतन हुआ या लेकिन वह भी थाडे समय के लिए। अत राज्यपाल की स्थिति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पडा । राज्यपाल की दुहरी स्थिति है। वह जहा राज्य का संबंधानिक अध्यक्ष है वहाँ केंद्र का अभिकर्ता भी है। उससे यह अपेक्षा की जाती है कि दलबदस् राजनीति एव सावजनिक नैतिक मानदण्ड के निरातर गिरते वातावरण म वह सविधान के सरक्षक एव लोकत न के सजग प्रहरी की भूमिका निमाय। राज्य पाल के यह को प्रभावी एवं अधिक उपयोगी बनाने के लिए निम्न सुभाव लामदायक हो सकत हैं

(1) राज्यपाल के पद पर निर्वाचना म पराजित दलीय राजनीतिना की ही

नियक्ति नहीं की जानी चाहिए।

(2) राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्य मित्रयों का स्पष्ट परामश लिया जाना चाहिए। स्मरणीय है कि केन्द्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करते समय सम्बर्धित राज्य के मुख्यमात्री के विचार नात कर लिय जाते हैं। यह स्वस्थ परम्परा है।

(3) राज्यपाल को नाममान के अध्यक्ष के स्थान पर सही अर्थों म सर्वधानिक

अध्यक्ष की भूमिका निभान के अवसर दिये जाने चाहिए।

(4) राज्यपाल को निध्यक्षतापूर्वक आचरण करना चाहिए। उसे के द्र से परामश के लिए निर तर नहीं दौडना चाहिए।

(5) राज्यपाल तथा विधानसभा एव मि त्रमण्डल के सम्बाधी को अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है। राज्यपाल के आदेश पर विधानसभा का तर त अधिवेशन वुलाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

(6) राज्यपाल के सम्भावित स्वविवेकी अधिकारी की स्पष्ट व्यारमा की जानी चाहिए।

राज्य की राजनीति मे राज्यपाल की भूमिका उसक व्यक्तित्व तथा मुख्यम त्री एव उसके सम्बाधा पर निमर करती है।

राज्य मन्त्रिमण्डल

राज्यों में सविधान के अनुसार मुख्यम ती की अध्यक्षता में एक मित परिपद का विधान किया गया है जा राज्यपाल को उसके स्वविवेकीय कार्यों का छाडकर शेप सभी कार्यों के सम्पादन में 'सहयोग एव परामश्व' प्रदान करेगा। 102 मुख्यम ती की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जायगी। श्रेष मित्रया की नियुक्ति मुख्यम त्री के परामश से राज्यपाल करेगा। 100 म तीगण राज्यपाल के प्रसाद पय त अपने पदो पर रहत है।

¹⁰² अनुच्छेद 163 103 अनुच्छेद 164

मित-परिपद राज्य विधानसमा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदावा हाती है। " मित्रयों के राज्यपाल के प्रसाद-पय त पदाख्व रहने का यह अब है कि राज्यपात मुख्यम जी के परामशे पर व्यक्तिगत रूप सं म जी को पदच्यून कर सकता है। 100 मीर मुख्यमन्त्री विधानसमा ना विश्वास मोने के पश्चात भी पदत्याग के लिए त्यार नहीं होता है तो राज्यपाल मुख्यमानी सहित मिन-मरियद को पदच्युत कर सन्त है। कुछ विद्वाना का यह मत है कि मन्त्रिमण्डल को राज्यपाल क्य नहीं कर सकता। लेकिन यह उसी अवस्था में सम्मव है जबकि मित्रमण्डल वैधानिक तरीके से सता का प्रयोग करता है और बहमत का समयन उसे प्राप्त होता है।

यदि कोई मात्री नियक्ति के 6 याह के भीतर विधानमण्डल के लिए नहीं चना जाता तो उसे मन्त्रिमण्डल ने पहत्याग करना पडता है। 100 सिवधार के अनुसार बिहार, मध्य प्रदेश एव उडीसा में एक एक जनजातीय विषयक मंत्री होता है। 10 मन्त्रियों के वेतन एवं मत्ता आदि का निर्धारण विधानमण्डल द्वारा किया जाता है। विधानमण्डल के दोनो सदनों के निर्वाचित एवं मनौनीत सदस्या की मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है।

सामा य काल म राज्य का मित्रमण्डल वास्तविक कायपालिका होती है।

मुख्यसन्त्री

राज्या के मुख्यमात्री की स्थिति के द्व न प्रधानमन्त्री के ही समकक्ष है। वह मिनमण्डल का अध्यक्ष एव विधानसभा म बहुमत दल का नता होता है । उसी क परामश पर राज्य के मित्र परिषद के अन्य सदस्य राज्यपाल द्वारा निमुक्त किय जात है। मुख्यम भी के पदत्यांग के साथ संस्पृष यित्रमण्डल को पदत्यांग करना पडता है। वह राज्य के मित्रमण्डल के जाम, जीवन एव मृत्यु के लिए उत्तरदायी हाता है। मिन्निमण्डल की बैठको की वह अध्यक्षता करता है। वह राज्य की सामा ॥ नीति ना निर्धारण करता है। वह प्रमुख प्रशासक एव शासकीय विमाण का निरीक्षक तथा सम वयकर्ता भी होता है।

वह राज्य के शासन का चालक वक है। उसकी शमता एव याग्यता पर शासन की सफलता निमर करती है। विधानमण्डल म वह शासन का प्रमुख प्रवक्ता होता है। वह मित्रया क मध्य उत्पन्न विवादा की तय करता है। इस सम्बंध में उसका निणय अतिम होता है। जा मात्री उससे सहमत नहीं होत उह पदत्याम करना पहता है।

¹⁰⁴ अनुच्देद 164 (2)

¹⁰⁵ महाराष्ट्र प्राप्त मधी की जड पलामपगार को उनक परत्याम न करन पर पदच्युत किया गया था । जा अन एक मधी को परच्युत किया गया था । 106 अनुब्दद 164 (4)

¹⁰⁷ अनुष्यद 164 (1)

उसे निमुक्ति सम्ब धी ब्यापक अधिकार हैं । राज्य के महाधिवक्ता एव लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष एव सदस्यों की निमुक्ति मुरयम नी के परामश्च पर ही की जाती है। समूज प्रशासन पर उसका निय तथा होता है। बहु मिन्नियदल एव राज्यपाल के मध्य कड़ी के रूप मकाय करता है। मुख्यम त्री की अनुमति के बिना कोई मंत्री राज्यपाल से सीधा सम्यक स्थापित नहीं कर सकता। मिन्नियष्टल के निजय मुरयम त्री हो हा स्वत्य हो स्थाप्त मानी हो कर सकता। मिन्नियष्टल के निजय मुरयम त्री हो हा स्वत्य नियास स्थापत नहीं कर सकता। मिन्नियष्टल के निजय मुरयम त्री हा सुंदर्य नियास स्थापत करें का अधिकार प्राप्त है। सुख्यम त्री को राज्य विधानसमा के विधादन की मौंग करने का अधिकार प्राप्त है।

बही वास्तद में राज्य की मुख्य कायपालिका है। वह मिन्त परिपद कपी मेह-राज की आधारिशला है। मुख्यम ती की स्थिति उसके व्यक्तित्व एव उसे प्राप्त दक्षीय समयन पर निमर करती है। काम्रेस हाई कमान का प्रसाप्त प्रथम ती की स्थिति के निर्धारण में निर्णायक होता है। प भीव दवत्त्वम पत, बिहार के थी श्रीकृष्ण सि हा बगाल के बियोगच द्वारा में हा के कामराज नाडर वहे सशक्त एव प्रमावशाली मुख्यम ती माने जाते थे। पर तु बहुत से मुख्यमियों का अपना कोई आधार ही नहीं था। वे काम्रेस हाईक्यान के मनोनीत प्रत्याशी भर होते थे। काम्रेस हाईक्यान के निर्देश पर अनेक राज्यों के मुख्यमियों की निपुक्ति होती रही है। उदाहरण के लिए, पजाब के स्वगीध मीमसेन सच्चर, मध्य प्रदेश के भूतपृत्व मुख्यमत्यों कलाशनाथ काटजू एव बतमान मुख्यम ती श्री सी सेठी। श्री सच्चर के पत्थात श्री प्रतापित्व करो कार्येस हाईक्यान के आदेश पर ही मुख्यम त्री कार्येस हाईक्यान के द्वाराषत्र के बाद 1964 ई मे श्री रामिक्यम पजाब के मुख्यम ती कार्येस हाईक्यान निश्चय मी कार्येस हाईक्यान ही करता रहा है।

प्रतापिंत् करो क विरुद्ध आरोपो नी जान के लिए एक आयोग की नियुक्ति के द्वीय शासन द्वारा की गयी थी। स्मरणीय है कि मुख्यम त्री राज्य की कायपालिका है। सिष्यान की किसी व्यवस्था के अनुसार के द्वीय मत्रिमण्डल को राज्य के मुख्य- मानी के विरुद्ध कायपाल कोई अधिकार नहीं है। यह दूसरो बात है कि राज्यपाल के माण्यम से के द्वीय सरकार कोई कायचाही करे। यह प्रस्त निस्चय ही बढा नाजुक है। अत प नहक ने कमीदास इननवायरी एक्ट, 1953 के अधीन मुख्यम त्रो करी वे विरुद्ध जीवा का लाजुक है। अत प नहक ने कमीदास इननवायरी एक्ट, 1953 के अधीन मुख्यम त्रो करी के विरुद्ध जीव का लादेश दिया था।

मुख्यम त्री वो नियुक्ति को लेकर अनेक बार ऐसी घटनाएँ हुई वो विन्ता का विषय वन नथी हैं। उत्तरदायी द्वासन के स्थापित एव मान्य अनिससया हा इन पट-नाओं से उस्तपम हुआ हैं। बहुमत दत्त के नेता को ही मुख्यमन्त्री पद के लिए राज्य-पाल द्वारा आमा पत किया जाता चाहिए। बिंदी विशो दल को स्पप्ट चहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल को स्वविवेक का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि मुख्य-म त्री के मित्रमण्डस के विरुद्ध अविद्वाय ब्यक्त किया जाता है तो राज्यपाल को

या तो नवीन निर्वाचन का आदेश देना चाहिए अथवा विरोधी दल क नता को वक हिपक सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित करना चाहिए। परन्त कमी कभी राज्यपाना ने इन मामलों में इन माय परम्पराओं का पूण निष्पक्षता के साथ पालन नहीं क्या है। 1952 ई में मदास के कांग्रेस मस्तिमण्डल के प्रत्याग करने ह पूर्व श्री राजाजी (चत्रवर्ती राजगोपालाचारी) को अनुच्छेद 173 (3) (e) एव 5 के अवीर

विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करने के लिए राज्यपान से सिपारिश की गया थी। विधान परिपद का सदस्य मनानीत होन के पश्चात श्री चन्नवर्ती राजगोपालाचारी की राज्यपाल ने मुख्यम की पद पर नियुक्त कर दिया था। इस घटना की तीव आलोचना

हुई थी। इसी प्रकार श्री मोरारजी देसाई को बम्बई का मुख्यमानी निम्क्त किया गया, जबकि वे निवधिनो मे विधानसमा का चनाव हार चुके थे। श्री मोरारजी देसाई की नियुक्ति समस्त नतिक एव सबधानिक औचित्य का उल्लंघन था। 1957 ई म उडीसा के मिनमण्डल के निमाण क सम्बन्ध में काफी घोटाला हवा था। 1958 ई म उडीसा के राज्यपाल थी बाई एन सुख तकर ने भी हरेकृष्ण महताब के त्यागपत्र को तरन्त स्वीकार न करके उचित काय नहीं किया था । उडान विरोधी दल के नेता से वकत्पिक सरकार की वार्ता शुरू कर दी थी और इसी वाच मे मेहताब को समभा-वृक्षाकर उनका त्यागपत वापस करवा दिया था।

राज्यों म भी संसदीय शासन का अनुगमन किया गया है और केंद्र की माति ही महिन्मण्डल अपने कार्यों के लिए राज्य विधानमभा के प्रति उत्तरदायी होता है।

सम्यण सी भ्रमण्डल एक साथ पदत्याग करता है और एक साथ पद प्रहण करता है।

सयुक्त राज्य ग्रमेरिका की कार्यपालिका—राष्ट्रपति [AMERICAN PRESIDENTIAL EXECUTIVE]

ससदीय कायपालिका के विषरीत अध्यक्षात्मक या अससदीय कायपालिका सक्ति पूचकरण के सिद्धा त पर आधारित है। स्ट्राग के अनुसार समुक्त राज्य अम रिका की कायपालिका—राष्ट्रपति—अध्यक्षात्मक कायपालिका का सबग्रेष्ठ उदाहरण है। अससदीय कायपालिका को स्थायी (fixed) कायपालिका की मी सज्ञा दी जाती है। है स्वयदस्यापिका द्वारा अपने पद से पृथक नहीं किया जा सकता।

अमेरिकी राष्ट्रपति विश्व के महान धासनाधिकारियों में गिना जाता है। इस पव के विकास में ऐतिहासिक आवस्थकता का प्रमुख योग है। अमेरिकी परिसय के सिवान (Articles of Confederation, 1777) का एक वडा दोग यह चा कि उसम कांग्रेस के निण्या एव सिध्या के किया बया हेतु के दीय कायपारिका का अमाव था। अत किशाई किया सम्भावन के समक्ष व्यवस्थापिका के समान ही कायपारिका को पर्याप्त का निमाण एक प्रमुख काय था। सम्भेवन म एक वय कायपारिका को पर्याप्त राक्ति सम्पन बनाने के पक्ष ये था ताकि शासन को स्थापित प्राप्त हा सके तो हुसरें वय का यह मत था कि यदि कायपारिका को यथिक शास्त्र वात सम्पन का मत था कि यदि कायपारिका को यथिक शास्त्र वात सम्पन को आलोचना करेगी। कुछ व्यक्ति एकक कायपारिका के तो दूसरे समान सत्ताथारी दो या तीन व्यक्तिया की बहुल कायपारिका के पक्ष म थ। अन्त म सम्भेवन ने यह निजय किया कि एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति होना चाहिए पत्त सम्भितन ने यह निजय किया कि एक ही व्यक्ति मा प्राप्त था कि राष्ट्रपति के लिए एक कायकारिणों परिपद की स्थापना की जाय जा अन्त म कि राष्ट्रपति के लिए एक कायकारिणों परिपद की स्थापना की जाय जा अन्त म कि राष्ट्रपति के लिए एक कायकारिणों परिपद की स्थापना की जाय जा अन महर प्राप्त था मा वा पा वा कि राष्ट्रपति के लिए एक कायकारिणों परिपद की स्थापना की जाय जा अन महर प्राप्त के लिए एक कायकारिणों परिपद की स्थापना की जाय जा अन महर प्रकृत की स्थापना की काय जा अन्त म कायपारिका स्थापना के स्थापना की जाय जा अन स्थापना की काय जा अन स्थापना की काय जा अन स्थापन कि राष्ट्रपति के लिए एक कायकारिणों परिपद की स्थापना की जाय जा अन सहस्य प्रवास के स्थापना की जाय जा अन स्थापन कि राष्ट्रपति के स्थापना की स्थापना की स्थापना की नाय जा अन स्थापन कि राष्ट्रपति के स्थापन की स्थापना की स्थापना की स्थापन की

I Strong op cat, pp 260-61

² अध्यक्षात्मन कायपालिना के लिए देखिए अध्याय 17

स्वीकार र द्वा सना । मीनट का सिष्या एवं नियुक्तिया के सस्वाय म कायकारिण परिपद के रूप म बाय करने के अधिनार प्रदान निये यय । सिषया एवं नियुक्तिया के सम्बाध म सोनट की स्वीकृति की व्यवस्था करने अवरोध और सानुतन की प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति की कायपालक हाक्तिया की सीमिन कर दिया गया है। एक तरक सीनेट का प्रतिय प स्थापित करक जहाँ राष्ट्रपति की निरकुद्धता की प्रतिविध्त किया गया, यहाँ दूसरी तरफ उस्त व्यवस्थापिता सं स्वताय तथा उसके पुन निर्वाचन की व्यवस्था करते राष्ट्रपति की सरकर राष्ट्रपति की व्यवस्था काया गया, यहाँ दूसरी तरफ उस्त व्यवस्थापिता सं स्वताय तथा उसके पुन निर्वाचन की व्यवस्था करते राष्ट्रपति के वर्ष का स्थायी वनाया गया है।

लास्की के अनुसार अमिरको राष्ट्रपति विटिश्च राजा से बडा भी है और घोटा भी है प्रधानमात्री से भी वह बडा एव छोटा है । उसके पद का जितना सतकता से अध्यानमात्री से भी वह बडा एव छोटा है । उसके पद का जितना सतकता से अध्यानमात्री से भी वह बडा एव छोटा है । उसके पद का जितना सतकता से अध्यानमात्री होता है । उस पार्थ होता है । अभिरिशी राष्ट्रपति को सविधान एव परम्परा उ इतने अधिक महत्वपुण बावित्व एव ततक्ष प्रधाद है कि लिक्डसे रोवर ने अनुनार उसका पूणक्षण सफल प्रशासक होना सावेह-जनक है । जास्की ने अनुनार, संयुक्त राज्य अभिरिक्ता के राष्ट्रपति से अधिक बावित्व विदय म किसी पदाधिकारी के नहीं है । अभिरिक्ता को केन्द्री के अपूक्त का प्रवासित्व प्रस्त का प्रमुख है। वह मुख्य कार्यपालिका ही नहीं अपितु मुख्य सेनापति, औप चारित्व प्रसूत्व एव विधासी तथा स्कीय नेता भी है।

अमिरकी राष्ट्रपति पद के लिए सिवधान के अनुसार वहीं व्यक्ति निर्वाधित हो सकता है जो सबुक्त राज्य अमेरिका का ज मजात नागरिक हा और जो 35 वप से कम आयु का न हो तथा जो 14 बागों से समुक्त राज्य अमेरिका म निवास कर रहा हो। साथ हो साथ जम के संगी गाम्यारों मी होनी चाहिए जो एक मतदाता के लिए आवस्पक होनी है। राष्ट्रपनि का बेतन एव जग जते सविधान हारा निर्वार्थित है। उहें उससे पदावधिकाल म कम नहीं निया जा सकता। 1909 ई से 1949 ई तक अमिरकी राष्ट्रपति का बेतन एउ हवार आति वय पा। 1949 ई में उसे बढ़ा कर 1 लाख जातर वार्षिक कर विधा या है। इसके अविरिक्त उसे 50 हजार आतर वार्षिक कर विधा करमें हमारे हमार बातर सार्थिक कर स्था गया है। इसके अविरिक्त उसे 50 हजार आतर वार्षिक कर मुक्त चनराशि गति कर स्था म मी प्राय हानों है।

राष्ट्रपति का कायकाल 4 वय है। वह अपने पद पर पुन निर्वाचित हो सकता

³ The President of the United States is both more and less than a king, he is, also both more and less than a Prine Minister The more carefully his office is studied, the more does his unque character appear "-Laski American Presidency, 1943 p 23

⁴ Lasks op at p 37

है। लेक्नि यह अभिसमय या परम्परा स्थापित हा चुकी थी कि कोई मी राष्ट्रपति निरत्तर तीसरे काल के लिए चुनाव नहीं लंडेगा । इस परम्परा की स्थापना का श्रेय प्रथम राष्ट्रपति जॉज वाधिगटन ना था जि होन तीसरी वार राष्ट्रपति पद पर चुना जाना स्वीकार नहीं किया था। 1875 ई में जनरल ग्राण्ट न तीसरी बार राष्ट्रपति चने जाने की इच्छा ध्यक्त नी थी लेबिन काँग्रेस ने इस पर यह प्रस्ताव पारित किया या कि दो बार राष्ट्रपति रहन के पश्चात तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी न होन की मुनिश्चित परम्परा माय है एव इसके विपरीत काय अविवकपुण, देशमस्ति विरोधी तथा देश की स्वतान सस्याओं के लिए घातक है। फ्लस्बरूप जनरल प्राण्ट न तीसरी बार चुनाव नहीं लंडा । गब्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट न तीसरी बार चुनाव लडा या परन्तु वे निवाचन म हार गये थे। फ्रेंक्लिन रूजवेल्ट ने इस परम्परा का उत्सपन करते हुए 1940 ई म तीसरी बार चुनाव लडा पा । इसम वे विजयो हुए तथा तीतरी बार राष्ट्रपति क्रते । 1944 ई म वे चौषी बार राष्ट्रपति चुने गये । परन्तु 1945 ई म उनकी मृत्यु हो गयी । द्वितीय विश्वयक्ष के कारण उत्पन्न सकट राष्ट्रपति सम्बन्धी इस परम्परा के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी था। भविष्य म इस प्रकार नी सम्मावना को रोनने के लिए 22वे सधी-धन (1951 ई) द्वारा यह व्यवस्था की गयी कि दो बार से अधिक काई व्यक्ति राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर सकेगा और यदि राष्ट्रपति की मृत्यू उसके कायकाल क दौरान म हो जाती है तो उप राष्ट्रपति शेष अवधि के लिए राष्ट्रपति पद ग्रहण कर सक्या और वह केवल दा बार राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्माशी हो सकेगा पर तु दोना बार सफल होन पर भी उसका कुल कायकाल 10 वय से अधिक नहीं हो सकेशा।

राष्ट्रपति का निर्वाचन

पानम् भवतः हा विधिनारं वापनं हिमा समा है। विद्युति परं हे प्रामाणिना ने व हि हो से ना विवाधक महर के महाना आसा महस्ति जात है। सन महरू स हिमा एक तम् प्रभी नार का दिया जा है जा विशेषक मारत के मन्त के राज का हितामा हिं। होगा । निधिकाम मा पा । ना र का राष्ट्रावि एवं उपने कम मन पार यात हो उन मानुनित युग नामा या। सन्ति र 20वें सनायन (1804 है) प्राय स्थ न्दरस्या को गामाण कर दिया गया एवं सोश पण के तिए पुषक-पुषक मनगत की ध्यवस्या का यक्ता है।

> 1 रेल

شلان

पर १ उपराक्त ध्यवस्या भी क्वल ४ वय तक हा यत सभी। 1796 १ व संवुक्त राज्य में वा राज शाहिक दना का उत्य हो गया और इस यप क निवाचन म यह स्वस्य या कि निर्वाधकमन एकम्म (Adams) या अवस्तान (Jefferson) म स एक मा अव ॥ मत दत । 1500 ह क प्रत्यात निवादर मण्डल क सभी सदस्य दसीव मा अप ११ मा २४ १ १०७० २ ७ प्रमात राज्याचर गण्या ११ समा सदस्य प्रतास आधार पर विवक्ति होने सब समा व अप इस के राष्ट्रपति पद में उम्मीरवार लाबार पर राज्याच्या देश राज प्रणाच क्या प्रणाच का राज्यात पर व प्रणादकार को ही अपना मत प्रमार करते हैं। इस परम्परा क विकास क प्रस्टवरूप राज्यां मा निवास अग्रतम् वर स्वत्यक्षरत् अत्यक्षः हो यद्या है। राष्ट्रपति क् ावाच । भागमा १४ मण्डा । विशेष प्रमुख समस्कि सबनीतिक देता क हारा सन्दर्शन नद्वा २६ थया हु । बाजा नद्वाच व्यवस्था अवस्थातम् । पा क वास्त सम्द्रपात एवं उप राष्ट्रपति यद के लिए निवायन सं बाको समय पूर्व स्तीय प्रस्पादिया क नामा प्र पर प्रभाव के कार्यों है। दला के डारा निवासक मण्डल की सदस्यता के लिए मी का पापणा र ६ व काम है। यह निर्माण के स्वरूपका का स्वरूपमा का १०६ मा अपने उम्मीदवार सहे किस जाते हैं। अहे निर्माणक मण्डल के सदस्या के निर्माण के अपन जन्मादबार एक १२ व गाँउ २ १ गाँउ । जन्मादबार गाँउपना क गाँपाना क साम यह निद्दिनत हो नाता है नि निस दल का उम्मीदबार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित दुगाव न नापराध्य ना का शास्त्र विश्व मता को शास्त्र करन का अधिकारी ही जाता है। ारिष अस राज्य का तमा गामानक मध्य का कार्य का भागकारा हा जाता है। उदाहरण में तिए ^क मूमाक राज्य से, जिसकी जनसंस्था 1 करोड़ 70 जात है 1961 वनाहरण र ११५८ प्रतिनिधि सदन एवं 2 सदस्य सीनेट के लिए चुने गये थे 1 मन ६ भ वा व्यस्य आवागाभ वचा द्रा के व्यस्य वाग्रक के व्यद् पुर वच व । भर (Maine) राज्य ना, जिसकी जनसंस्था । लाल के करीय है 4 संस्थ (2 संस्थ (Manne) १००० र १) (जिल्ला) विशेषक में प्रतिनिधित्व करते हैं। अत राज्यति भारतामाथ चवन चवन ४ त्याच्य व्यास्त्र राज्य को नामाणावाच्य परत है। वस सम्द्रपात के निर्वाचक मण्डल म युमाक राज्य को 43 सदस्य और मेन राज्य को चार सदस्य क । पाना वन १९०६ में प्रमान पान के प्रमान भैजने का अधिकार है। परंतु निर्वाचक मण्डल ने सदस्या क निर्वाचन में जिस दल के भेजन का आधकार हु । पर पु राजानक कण्का प छश्टरा क स्वताचन म ।जस दल क प्रत्यावियों को अधिक मत प्राप्त होंग, उसी दल के राष्ट्रपति पद के उपमोदनार को 5 1972 ई कं राष्ट्रपति कं निर्वाचन म निर्वाचक मण्डल की सदस्य सस्या

⁶ Strong op cut p 263

उस राज्य के सभी निर्वाचक मण्डल के सदस्यों के मत प्राप्त होगे। इसस यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन मे उम्मीदवार बडे राज्यों के सहयोग पर ही अधिक-तर निर्मर रहता है। इस व्यवस्था का एक गम्भीर दोप यह है कि कुछ बडे राज्या का समयन प्राप्त करने वाले. लेकिन कुल जनता के कम मत प्राप्त करने वाले. जम्मीदबार विजयी हो जाते हैं। स्ट्रांग ने कुछ प्रमाण इस मत की पृष्टि में दिये है 1860 ई म अब्राहम लिंकन को 180 निर्वाचक मत और उसके तीन विरोधिया को 123 मत प्राप्त हुए थे। लिंकन के निर्वाचकों को 18,60 000 मतदाताओं ने चना या, जबिक उनके विरोधियो को 28,10 000 मतदाताओ द्वारा चुना गया था। स्पष्ट है लिकन देश के 40% मतदाताओं के समयन पर ही चुन लिये गये थे। 1888 ई में हेरीसन को 223 निर्वाचक मत प्राप्त हुए थे और उनके विरोधी क्लीवलैण्ड को 168 मत. जबकि क्लोक्लण्ड के निर्वाचकों को 96 हजार स भी अधिक अतिरिक्त मतदाताओं का समधन प्राप्त था। क्लीवलैण्ड का समधन दक्षिणी राज्यों ने किया था जिनकी जनसरया अधिक थी पर तुनिर्वाचक मण्डल में इन राज्यों के सदस्यों की सख्या कम थी। 1912 ई मे राष्ट्रपति विल्सन को 435 निर्वाचक मत प्राप्त हुए थे. जबकि उनके तीन विरोधिया को 96 मत मिले ये लेक्नि विल्सन को अपने विरोधियों की तलना मे 23 22.453 मत कम मिले थे। यह दौप हाल के निर्वाचना मे और मी स्पब्द हो गया है। 1940 ई में रूजवेल्ट को 449 मिर्वाचक मत प्राप्त हुए थे, जबकि वेण्डले विलकी को 82 मत मिल थे, लेकिन 4 करोड 90 मतदाताओं में से रूजवेल्ट को केवल 5 लाख मत अधिक प्राप्त हुए थ । 1948 ई मे राप्ट्रपति टूमैन को 189 के विपरीत 304 निवाचक मत प्राप्त हुए थे, जबकि ज ह केवल 21 लाख मत अधिक प्राप्त हुए थे । 1960 ई म जान एक केनेडी न रिपब्लिकन दल के विरोधी प्रत्याक्षी निक्सन को 87 निवाचक मतो स पराजित किया था, जबकि है करोड 80 लाख कूल जनता के मतो में से उसे केवल 1,12,881 मत ही अधिक मिल थे।

उपरोक्त दोप को दूर करने के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति क स्थान पर प्रत्यक्ष प्रणाली अपनाने के कई बार सुभाव आये हैं। सविधान निर्माताओं ने यह कभी कल्पना नहीं की थी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता की इच्छा पर निमर रहन लगेगा एवं उसमे राजनीतिक दलो हारा महत्वपूण भूमिका निमाई जायेगी। उपरोक्त होप

^{7 1972} ई के अमरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन के कुछ सध्य बडे राचक हैं। निश्तन की प्रचण्ड बहुमय प्राप्त हुआ था। 50 में से 49 राज्या म निश्तन के पक्ष म मतदान हुआ था। केवल एक राज्य समाच्युत्रदल न प्रचणन के पक्ष म मतदान किया था। 538 निर्वाचको म से 521 मत निश्तम को तथा। 17 महम्मतन का प्राप्त हुए थे। 1968 ई के राष्ट्रपति चुनावा म जहाँ 73% मतदाताओं न मतदान किया था, यहाँ 1972 ई म कवल 55% मतदाताओं ने ही माग लिया था।

के बावजूद मी यह एक स्वीकृत तथ्य है कि अमेरिकी राष्ट्रपति सविधान निमाताओं की इच्छा के विपरीत अब व्यवहार म प्रत्यम रीति से निर्वाचित होने लगा है बी अपेसाकृत अधिक लागतान्त्रिय व्यवस्या है।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ एव अधिकार

समेरिकी राष्ट्रपति व्यापक शक्तिया स मुक्त विस्व का प्रमुख शासनाधिकारी है। यह शक्तियों उस सविधान, गोंग्रेस की विधियो, परम्पराक्षा एवं यायिक निणयों से प्राप्त इहें हैं।

कायपालिका शक्तियाँ

संयुक्त राज्य अमिरका का राष्ट्रपति राज्य और कायवासिका होगो ना ही अध्यक्ष है। वह देश का प्रमुख प्रधान्य है। राज्य की कायपासिका गिक्त राष्ट्रपति मित्रित है। मुख्य पायपासिका के रूप मे देश के सिव्यान, विधियो एव पियान सित्रा सपीय पायपासिका के निष्णा को देश मर मे विधानित करना राष्ट्रपति का ही शामित है। वह कविस नो विधियो हारा विधिरित कार्यों के नियान वस्तु ही सामित है। वह कविस नो विधियो हारा विधिरित कार्यों के विधान में शाम प्रदेश हो है। विधान ने शाम रूप विधान है। सर्वोच्च अध्यक्ष स्वाप्त है के अनुसार विधियों का भनी गांति किया वधा जनका सामित्र है। तथा वधा जनका सामित्र है। तथा वधा जनका सामित्र है। तथा वधा जनका सामित्र है कि स्वाप्त अपने कार्यक्ष का मत्री है। वह सपीय प्रधानकी अधिकारियों एव सपीय व्यायाधीयों को नियुक्त करता है। तकिन इन नियुक्तियों को मीनट के से तिहार बहुन्त से अनुमीदित होना चाहिए। इच्च पदा, जसे, गांत्रीम सामावीय एव सपीय व्यायाधीया को स्वाप्त करता है। लेकिन इन नियुक्तियों को मीनट के से तिहार बहुन्त सभी यह सपीय व्यायोग के कप्यक्षों एव सर्वस्था को नियुक्तियां राष्ट्रपति सीमट के अनुमादत से ही करता है। क्षित वैश्व की 80% शासकीय नियुक्तियां लोकसेवा नायोग हारा नी कार्ती है।

कभी कभी सीनेट ने राष्ट्रपति द्वारा की गयी नियुक्तियों को अस्बीकृत किया है। पर तु कुछ राष्ट्रपति सीनट द्वारा अस्वीकृत पदाधिकारियों को अपने पद पर बनाय रखन म सफल रहे थे। सीनेट जिन नियुक्तियों का अनुमीदित नहीं करती वे केवल सीनेट के सन क अन्त तक ही चलती हैं। इह अवकाशकालीन नियुक्तियों या अस्सायों नियुक्तियों कहते हैं। सीनेट के सन नी समाध्ति के परचात राष्ट्रपति यदि चाहे ता पुन उसी व्यक्ति का उसो पद पर नियुक्त कर सनता है और इस प्रकार सीनट की इच्छा न विपरीत भी नियुक्ति को आरो रख सकता ह। राष्ट्र-पति न सिल ने इसी प्रकार चाल्त थी बारेन को अटोनीं जनरस के पद पर कायम रखा था। तेकिन इससे सीनेट के अस तुष्ट हो जाने का भय रहता है।

नियुक्तियो ने सम्बन्ध में सीनेट ने बीज व (Senetorial Courtesy) नामक प्रवा का विकास हुआ है। इस प्रवा के फ्लस्करूप राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली नियुक्तिया को सीनेट स्वीकृति प्रदान कर देती है और राष्ट्रपति द्वारा की गयी नियुक्तिया का कदाजित ही विरोध किया जाता है। सीनेट के सीज य का यह जय है कि राष्ट्रपति जब किसी सधीय अधिकारी नी विन्धी राज्य के सीन ये नियुक्ति करता है अर्थात स्थापी नियुक्ति करता है अर्थात स्थापी नियुक्तियाँ करता है तो उसे उस राज्य के सीनेटर से नियुक्ति कर ता राज्य कर सेना चाहिए। यदि सीनेटर राष्ट्रपति के प्रस्ताय स सहमत है तो सीनेट के अप्ताय कर सेना चाहिए। यदि सीनेटर राष्ट्रपति के प्रस्ताय स सहमत है तो सीनेट के अप्ताय कर तेने चाहिए। यदि सीनेटर राष्ट्रपति के प्रस्ताय है सहम है तो सीनेट के प्रमाय कर तेने हैं। लिक्त राष्ट्रपति है। यदि सम्बित नियुक्ति की सहन ही स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। लिक्त राष्ट्रपति द्वारा अस्तावित नियुक्ति सीनेट हारा अनिवायत सस्योक्त कर दी जाती है, यदि सम्बत्तिय ताग्य के राष्ट्रपति कजबस्ट ने बेस्ट कर्जी ही नियुक्ति पर आपत्ति हो। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति कजबस्ट ने बेस्ट कर्जीनिया के सदीय जान पायालय म क्याइर एच राबट की प्राथिश के पद पर नियुक्ति की थी। उस राज्य का गवनर इस नियुक्ति के पक्ष म या पर सु दोनो किया था।

सिंदिपान निर्माता सीनेट हारा नियुक्तिया की स्वीकृति को राष्ट्रपति की शक्तिया पर एम प्रतिवाध मानते थे। पराचु यह व्यवस्था शीछ ही राष्ट्रपति को अवाछनीय रूप स प्रमायित बरन के लिए सगठित राजनीतिक दशव के रूप म प्रयोग की जाने नगी है।

राष्ट्रपति का पदाधिकारिया को पदध्युत करने को सक्ति भी धापत है। याया धीसा को छोडकर नह जन समस्त अधिकारियों को जिन्हें वह नियुक्त करता है, पदच्युत कर सकता है। 1876 हैं में प्रेतीडेयर जाससन एव काग्रेस में इस सम्बद्ध में एक विवाद उत्तम हुआ था। फलस्वरूप काग्रेस ने एक विवाद उत्तम हुआ था। फलस्वरूप काग्रेस ने एक विवाद उत्तम हुआ था। फलस्वरूप काग्रेस ने एक विवाद उत्तम हुआ था। फलस्वरूप विवाद स्वाद्ध को परिकृत निर्मा के परिकृत कर सम्बद्ध को राष्ट्रपति विवाद ने एक पोस्ट मान्टर मिस्टर सेयस को पदच्युत कर विवाद । पायालय ने 1876 ई की काग्रेस की उपयुक्त विवाद को मयस बनाम समुक्त राज्य कार्यक्ति का स्वाद ता समी प्रमुक्त परिकृत कर विवाद पायालय के अवस्थानिक घोषित किया था। बत राष्ट्रपति सभी प्रमासकीय पदाधिवारियों को अपनी इञ्जानुसार पदच्युत कर सकता है। लेकिन निरामकीय आयुक्ती (Regulatory Commissioners) की स्थित इससे मिन्न है। उनके कद्य-यायिक अधिकारी होने के कारण उन्हें विधि का सरस्वा प्राप्त है।

वैद्याक मामलो म अमेरिकी राष्ट्रपति को अत्यधिक विस्तृत एव व्यापक शक्तियाँ प्राप्त है। यह राजदूता को नियुक्ति करता है एव विदेशी राजदूतो का स्यागत करता है। वह देश की विश्व नीति का निर्माता है। सीनेट की सहमित में वह सिंधयों करता है। इसके लिए सीनेट के दो तिहाई बहुमत का अनुसमयन आवस्यक है। लेकिन राष्ट्रपति को सीनेट की सहमिति क विना हो कायकारिकी समगीत (execultive arrangements) करन का अधिकार है। वह समगीत व्यवस्था म सिंग्या को मौति ही त्रवावसासी हात है। व्यापारिक समगीते नी काकारियों समगीते की काकारियों समगीते की काकारियों समगीते की प्रांत करते मही। यासी रिजया म यान के सिए किय जात है। 1937 ई. म. अमेरिती राष्ट्रपति हारा 10 सिंप्या तथा 27 क्यारियों समगीते किय में। अन्त रिष्ट्रियों सिंपित हारा 10 सिंप्या तथा 27 क्यारियों समगीते किय में। अन्त रिष्ट्रियों सिंपित कारा व्यापक स्थान स्थान स्थान स्थान करन के निष्ट्रियों स्थिति कारा व्यापक स्थान स्थान

राष्ट्रपति विदेश नीति ना अभिकृत निर्माता एव ध्यास्याता होता है पर्छी
सर्विधान म स्पष्ट राज्ना म यह उस्तिशित नहीं है। तेकिन मर्वोच्च याधातय हारा
ध्यक्त सवधानिय ध्यास्थाया म राष्ट्रपति को विदेश नीति ना निर्माता माना नया है तथा
त्यास्य यो अधिकार भी उस प्रदान किय नय हैं। सर्वोच्च याधातय के अनुसार राष्ट्र
पति ना संधीय ग्रासन क पूष्य अधिकारी क रूप म अत्यरिद्धीय क्षेत्र म सर्विधान की
धाराआ व अधीन शक्तिया वा प्रधान करना चाहित । राष्ट्रपति के राजदूता को
नियुक्त करन एव हसर दशा के राजदूता का स्वागत करना के अधिकार से अय दशा
को सायता देने की शक्ति निहित है। विसी देश को मा यता देना या न दना
राष्ट्रपति के स्वधिके पर निजर करता है।

राध्यपित को अप देशा के साथ समझौते करने का अधिकार काँग्रेस दे सकती है। उदाहरणाय, 1938 ई के Reciprocal Trade Act द्वारा गान्यित को विद्या स व्यापारिक समझौते करने का अधिकार दिया गया था जिसके अधीन वह सीनट की स्वीकृति ने दिना ही करा म 30% तक की कमी पर मकता है।

राष्ट्रपति को तैनिक शक्तिया भी आप्त है। वह देश की जल यल एवं वायु सेनाओं का मुख्य केनापति है। उसे सीनट की अनुस्रति से सैनिक एवं गौसिनिक अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार है एवं युद्धकाल में वह उन्हें इच्छानुसार पदच्युन कर सकता है। सुख्य सेनापति के रूप म राष्ट्रपति को देश की रक्षा एवं शक्नुओं को परास्त करने वे निए आयस्यक कदम उठाने का अधिकार होता है।

काग्रेस को युद्ध की घोषणा का अधिकार प्राप्त है तेरिकन युद्ध को स्वधित करने एव समाध्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति विदेश मीति के सवालन के द्वारा ऐसी परिस्थितियों उत्पन्न कर सकता है कि युद्ध अनिवास हो जाये। उदाहरणाथ द्वितीय विष्य युद्ध के प्रारम्म के वृद्ध तथा बाद भ राष्ट्रपति

इस प्रकार न नायकारिणी समफीत के कुछ उदाहरण हैं प्रोटाकोल (1901 ई) अटलाण्टिक चाटर (1941), विघ्यसक उड्डा (Destroyer's Base) समफीता।
 Curtis Wright Case U S 1936

रूजवेल्ट ने धुरी राष्ट्रो के विरुद्ध मापण दिये थे। राष्ट्रपति मैक्निले न हवाना क लिए एक जगी जहाज भेज दिया था। इस घटना ने स्पन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा को अनिवाय बना दिया था। 1918 ई मे राष्ट्रपति विल्सन ने साइवेरिया मे मित्र राष्ट्रा की सेना के सहायताथ अमेरिकी सैनिक भेजे थे जब कि रूस व अमेरिका मे युद्ध की स्थिति नहीं थी। राष्टपित जिल्सन ने जमन राजदूत की चेतावनी के बावजुद भी सुसीटानिया जहाज को इगलण्ड भेजा था । राप्ट्रपति हार्डिज एव कलिज ने करेबियन देशों में अराजकता को दबाने के लिए सना भेजी थी। 1941 है मे राष्ट्रपति रूजवेल्ट के काल मे जमनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के पूर्व ही अमेरिकी नौसेना न 1940 ई म ही जमन पनडुब्बियो पर आक्रमण प्रारम्म कर दिये थे। 1950 ई मे राष्ट्रपति टू.मैन ने अमेरिकी फीजो को कोरिया मे आक्रमणकर्ताओं के प्रतिरोध के आदेश काग्रेस से अधिकृत किये जान के पूर्व ही दे दिये थे। युद्ध प्रारम्म हो जाने पर राष्ट्रपति की कायपालिका एव सैनिक शक्ति म असीमित बद्धि हो जाती है । सेनापति के रूप म वह युद्ध राजनीति सम्बाधी अतिम निणय करता है। अब राष्ट्रपति को अण्वम के प्रयोग के जसीमित अधिकार प्राप्त हो गये हैं। काग्रेस उसकी सत्ता म बद्धि कर सकती है। प्रथम युद्ध काल मे प्रेसी-डेण्ट विल्सन को काग्रेस ने उत्पादन नियातित करने, युद्ध हुत विभिन्न वस्तुओं के मूल्य निधारित करने एव सेना के लिए खाद्य सामग्री को उपलब्ध करने के लिए अधिकार प्रदान किये थे। द्वितीय विश्वयुद्ध काल मे राष्ट्रपति रूजवेल्ट को व्यापक अधिकार दिये गये ये जिनके फलस्वरूप वह कम बढ सवधानिक तानाझाह ही बन गये ये। काँग्रेस की विधि के अधीन विजित प्रदेशा म सैनिक शासन स्थापित करने का अधि-कार राष्ट्रपति को है। उदाहरण के लिए, द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात इटली एव जापान में सैनिक वासन की स्थापना की गयी थी। राप्टपति देश म सधीय विधिया को किया वित करने क लिए भी सेना का प्रयोग कर सकता है।

सकट-काल म काँग्रेस राप्ट्रपति को ब्यायक विक्तिया प्रदान करती है। सकट-काल की ब्याख्या करने का अधिकार राप्ट्रपति को है। राप्ट्रपति क्जबेल्ट द्वारा इन शक्तिया के अधीन अधिकायो (बैंका) की छुटिटया घोषित की गयी थी एव स्वण का आमात व निर्यात निष्दि कर दिया गया था। दितीय विश्व-गुद्ध की घोषणा के परचात अनेक विधियों कांग्रेस द्वारा पारित की गयी थी जिनक फलस्वरूप राप्ट्रपति को सामा-विकाजीवन के प्रत्येक क्षेत्र म निय गण सम्ब घी व्यायक अधिकार प्राप्त हो गय था। विधायों गक्तियाँ

काँग्रेस का सदस्य न होते हुए भी राष्ट्रपति को व्यापन विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। राष्ट्रपति कप्रिस के नाम संदेश भेजता है और विधि निमाण म महत्वपूण भूमिका निभाता है। कभी कभी इन संदेशा के माध्यम से राष्ट्रपति विधि विभेष को नारित करने की आवश्यकता एवं वाद्यनीयता पर वल दता है। कथ्रिम के नाम राष्ट्रपति

के सादणा का अवस्ति राजनीति म निरीप महत्व है। इन सन्दरों के माध्यम सं, ज मुरूप गमा भर-पत्रा म प्रकाशित होते हैं, राष्ट्रपति जनता की प्रमावित करता है। रमी-नमी स देशा वा उद्देश विदशी राज्या को सम्बोधित करना होता है तथा उनक द्वारा दश की विदश नीति के मीलिक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जाता है, जर्म, मुनरो सिद्धात । राष्ट्रपति व साम्या की उपक्षा निमी कांग्रस क लिए वर सकता सम्मन नहीं है।

राष्ट्रपति का कांग्रस क विरोध अधिवदान आहत करने का अधिकार प्राप्त है। राप्ट्रपति कांग्रेस की सामा य अवधि की आवश्यक विधि निमाण हेत् बढाने की मौग पर मरता है। यदि गाँग्रेस स्वीकार नहीं गरती तो वह विशेष अधिवेशन बाहुत कर सकता है। कांग्रस के विरोध अधिवेशन आहुत करन के लिए राष्ट्रपति एक घोषणा बरना है तथा उसके उद्दश्य को स्पष्ट करता है। हमरणीय है कि सामा यस राष्ट्रपति को गांपस के अधिवदान को स्थागत करन का अधिकार नहीं है सकित दोनों सदनी में विवाद की स्थिति में वह काँग्रेस का अधिवेशन स्थगित कर सकता है। इस गाँक के प्रधान का अभी तक अवसर नहीं आया है क्योंकि काँग्रेस का मदैव ही इस सम्बन्ध में एकमत है।

कायकारिको आणाप्तिमाँ (Executive Orders) जारी करनेका अधिकार राष्ट्रपति को कांग्रेस ने प्रदान किया है। इनकी तुलना हम प्रदत्त विधान (delegated legislation) से कर सकते हैं। कांग्रस के पास विधि निर्माण मम्बची अत्यधिक काय रहता है अत वह राष्ट्रपति का विधि के अधीन आदश जारी करन का अधिकार प्रदान कर देती है। राष्ट्रपति द्वारा इस अधिकार का व्यापक रूप मे प्रयाग निया जाता है।

राष्ट्रपति काँग्रेस द्वारा पारित विधेयको पर हस्तान्दर करके उन्ह स्वीकृति प्रदान करता है। तत्पश्चात ही वे विधि वनते हैं। वह काँग्रेस द्वारा पारित समस्त विधे यका का स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है। विधिया को अस्वीकृत करने की धांकि को निर्पेधाधिकार (Veto) की सज्ञा दी जाती है। राष्ट्रपति को दो प्रकार के निवेधाधिकार प्राप्त हैं--- पूर्ण' तथा 'अस्यामी' निपेधाधिकार । यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को 10 दिन के भीतर अपनी वापत्तियो सहित उस सदन को जिससे बहु सब-प्रथम प्रस्तावित किया गया था लौटा देता है और काग्रेस के दोनो सदन 2/3 बहसत से प्रयक-पथक रूप मे उस विधेयक को पुन पास्ति कर देने है नो वह विधेयक राप्ट्रपति की स्वीकृति वे अमाव मं मी विधि वन जाता है। इसमें अतिरिक्त राप्ट्रपति यदि किसी विधि प्रस्ताव का प्राप्त करने के 10 दिन के भीतर अस्वीकृत नहीं करता और न उस पूर्निक्चार हेतु काँग्रेस को ही चौटाता है नो वह विधेयक स्वयमेव ही विधि वन जाता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई विध्यक राष्ट्रपति क समक्ष प्रस्तुत निया जाता है लेकि। वह उसके सम्बाध म कोई कदम नही उठाना तथा राष्ट्रपति नी

विषेत्रक भेजने क 10 दिल म ही कांग्रेस का अधिवेदाल भी स्थिगत ही जाता है तो वह विधेयक स्वत ही समाप्त हो जाता है। इसे जेवी निषेधाधिकार या पीकिट बीटो (Pocket Veto) कहते है। मह पूर्ण रूपेण निरमक्ष (absolute) होता है। बहुधा कांग्रेस क सत्र क अतिम दिनो म बहुत से विषेयक काय समाप्ति के लिए शीघरता मे नारुष गुप्त के नार्वा विश्व के स्थान के बहु विश्व होता है पारित कर दिये जाते हैं। राष्ट्रपति ऐसे विधेयको पर, जिनके वह विश्व होता है तथा जिनकी असफलता का दावित्व वह स्वय वहन नहीं करना पाहता, कोई कायवाही नहीं करता है अर्थात् न तो हस्ताक्षर करता है और न काग्रेस को ही सीटाता है। फतस्बरूप वे विधेयक स्वयमव ही समाप्त हो जाते है।

राष्ट्रपति निषेपाधिकार का प्रयोग सम्पूण विषेपक पर करता ह, उसके किसी अद्य पर नहीं । सबैधानिक संशोधना पर नियेशिषकार का प्रयोग नहीं किया

जा सकता है।

प्रारम्मिक राष्ट्रपतियो, बाधिगटन आदि ने निषेवाधिकार का प्रयोग केवल असर्वधानिक विधियों के विरुद्ध ही किया था। राष्ट्रपति जैक्सन ने सवप्रथम इस अधिकार का प्रयोग कायपालिका के अधिकारों को व्यवस्थापिका के अतिक्रमण से बचाने के लिए किया था। अब नियेषाधिकार का अधिक प्रयोग किया जाता है। प्रथम छ राष्ट्रपतिया न केवल 3 विवेयका को अस्वीकृत किया था। इसके विपरीत, राष्ट्रपति फेक्सिन डी रूजवेस्ट ने 631 विशेषको पर निपेशिषकार का प्रयोग किया राज्याम काराना व विवेधक पुनिववार क लिए कविस को भेजे जाते हैं, वे शायद ही कांग्रेस द्वारा पुन पारित किय जाते हा क्योंकि कांग्रेस के पास सदव ही समय का ्र अभाव रहता है। राष्ट्रपति आइजनहोवर के पूत्र तक 1190 वार निपेषाधिकार का प्रयोग क्या गया था। इनमें से केवल 71 निषेधाधिकार काप्रेस द्वारा विषेषकों के पुन पारित करने के कारण निष्प्रमानी हो गय थे।

राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करते एव प्राणदण्ड को स्थागत करने के अधिकार प्राप्त है। इन अधिकारों का प्रयोग वह नानवीय आधार पर करता है। उसकी -यायिक शक्तिया ता प द । वा जानकार का जवान नहीं वा स्वीकृति से वह इसका प्रयोग नहीं यह शक्ति निरपेक्ष है । किसी के सहयोग एवं स्वीकृति से वह इसका प्रयोग नहीं करता । परतु वह केवल सभीय विधिया से सम्बधित अपराधियों को ही क्षमा प्रदान कर सनता है। महानियोग के दोषी और राज्य विषयो के उल्लंपन के दोपी अपराधियों को वह क्षमा नहीं कर सकता है । उसे सावजनिक क्षमा प्रवान करने का भी अधिकार है। समय-समय पर अनेक राष्ट्रपतिया द्वारा इस द्वांत का प्रयोग किमा गया है। सावजनिक क्षमादान के अ तगत ही Sedition Act, 1798 के अघीन दण्डित सभी अपराधिया को राष्ट्रपति ने क्षमा किया था। 1865 ई मे समुक्त राज्य क विषद्ध सदस्त्र विद्रोह करने बाल सभी व्यक्तियों को कुछ सतौं पर राष्ट्रपति जॉन सन ने क्षमा प्रदान की थी। दण्ड के पूब एव पश्चात दोना ही अवस्थाआ म राष्ट्रपति क्षमा नर सकता है। ध्यवहार म राष्ट्रपति सामान्यत इस अधिकार का प्रयाप स्व न करके न्याय विभाग की सिफारिसा पर काम करता है।

राष्ट्रपति सविधान को रक्षा की शर्य भवा है वत सविधान की रक्षा करता उसना दावित्व है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोज्व यायालय के द्वारा वाला में सिषधान क मरक्षक का दावित्व निमाया जाता है। कायपालिका के रूप में एद्यूरी के कार्यों का सविधान विरोधी होने पर सर्वोज्व न्यायालय उन्ह असवधानिक पाँखी कर मकता है। 10

कांग्रेस एव राष्ट्रपति

अमरिकी सविधान निर्माता राष्ट्रपति को महत्त्वाकाक्षा तथा दलव दी से मुक रखकर, हैमिस्टन के शब्दों में, उसे अराजवता के विरुद्ध प्रधान अवरोध बनाना चाहत थे। इसीलिए उसके अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गयी थी। वे कार पालिका को पालिकाली बनाना बाहते ये जिससे कि राष्ट्रीय सरकार स्थायी, गर्ति वाली एव सक्षम हो सक् । सविधान निर्माता कामपातिका का अत्यधिक शक्तिशाली बनाने के दोषा से मली प्रकार परिचित थे। अत राष्ट्रपति की शक्तियो पर सीनेट व सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिबाध स्थापित किये क्ये हैं। राष्ट्रपति द्वारा की जान वाली सभी नियक्तिया एवं सचियों के अनुसमयन का अधिकार सीनेट की दिया गया है तथा काँग्रेस की शासन के तीना अगा की शक्तिया के प्रयोग के सम्बाध म निधि निर्माण क अधिकार हैं। अत विधि निर्माण एवं कायपालिका विभाग के अन्य अधीनस्य अपी के निर्माण के लिए राष्ट्रपति काँग्रेस पर निभर है ।11 तेकिन परित प्रथकरण के सिद्धान्त के कारण क्षेत्रस एव राष्ट्रपति दोनो ही एक दूसर से पर्याप्त स्वतात्र है । दोनो का कायकाल सुनिविचत है। काग्रेस मले ही राष्ट्रपति से अस तुष्ट हो लेकिन महामियीग के अतिरिक्त किसी अय रीति से शास्त्रपति को अपने पद स पृथक नहीं कर सकती। यह महामियोग की व्यवस्था मी वडी जटिल है। व्यवहार म इसका प्रयोग केवल एक बार 1868 ई मे राष्ट्रपति ए इ जनसन के विरुद्ध किया गया था वह भी असपस रहा और महामियोग पारित न हो मका । राष्ट्रपति के विरुद्ध देशद्वाह, उत्कोच या ऐसे ही किसी अपराध या महापातक सम्बन्धी आराप प्रतिनिधि आगार द्वारा समाय जाने तया सीनेट द्वारा जीव के पश्चात 2/3 बहुमत से आरोपा के सिद्ध होने पर राष्ट्रपति के विक्य महामियोग पारित हा सकता है एवं उसे पदच्यत किया जा सकता है।15

¹⁰ समुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च यायातय के अधिकार व कत्वा के लिए देखिए अध्याय 25 ।

¹¹ Beard American Government & Politics 1949, p 200

¹² राष्ट्रपति रिवाड निवसत के विरुद्ध महािमयोग की चर्चा काफी गरम रही थी, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया।

राष्ट्रपति एव काग्रेस म प्रशासकीय प्रश्नो पर सघप होते रहे है और राष्ट्र-पति द्वारा अधिकाधिक शक्ति हथियाने के प्रयत्न का काग्रेस ने समय समय पर विरोध किया है। राष्ट्रपति जैवसन एवं कांग्रेस में टेजरी के प्रश्न पर तीव्र मतभेद उत्पन हुआ था। राष्ट्रपति जनसन का मत था कि ट्रेजरी विमाग की नीति की उन्ह काग्रेस की विधि के बिना ही नियातित करने का अधिकार है। राष्ट्रपति क्लीवलैण्ड ने शासकीय कमचारियों के निय्कासन सम्बाधी कागजों को काग्रेस को दिखाने से इ कार कर दिया था। 1954 ई में सीनेटर मकार्यी ने यह माग की थी कि कायपालिका कमचारियो एक जनसे सम्बंधित निणयों को राष्ट्रपति द्वारा काँग्रेस की समितियों के समक्ष प्रस्तत करने से नहीं रोका जाना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति आइजनहोवर ने इस माग को अस्वीकार कर दिया था। इस प्रयत्न को उन्होंने राष्ट्रपति की सविधान प्रदत्त शक्तियो को काग्रेस द्वारा हडपने की सज्ञा दी। राप्टपति एव कांग्रेस मे विशेष का मृत्य कारण यह है कि राप्टपति जनता द्वारा निर्वाचित होने के कारण अपने की सम्पूण राप्ट का प्रतिनिधि मानता है। इसके विपरीत, काग्रेस के सदस्य विभिन्न क्षेत्रो (मतदान-क्षेत्रो) से चने जाते हैं। यदि कांग्रेस में राष्ट्रपति के दल का बहुमत नहीं होता तो दोनों में विरोध अपेक्षाकृत बढ जाता है। संकट काल म काँग्रेस सामा यत राप्ट्यति का नेतरव स्वीकार कर लेती है। लेकिन सकट के समान्त होने पर काग्रेस राष्ट्र-पति के नेतृत्व को अस्वीकार कर देती है। उदाहरण के लिए, फेंकलिन डी रूजवेल्ट के राष्ट्रपति बनने के समय अमेरिका 1930 के दशक की विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी के अभिशापों से सत्रस्त था। अत सत्तारूढ होने के 100 दिन तक काँग्रेस ने उन सभी विधेयको को पारित किया जिल्ह राष्ट्रपति चाहता था। लेकिन बाद म स्थिति बदल गयी। प्रथम विश्वयुद्ध काल से राष्ट्रपति विल्सन का काग्रेस द्वारा विरोध नहीं किया गया लेकिन युद्धोपरा त ही राष्ट्रपति बिल्सन द्वारा की गयी वार्साई सीध का अनुमोदन सीनेट ने अस्वीकार कर दिया या।

राष्ट्रपति दल के नेता के रूप मे

राष्ट्रपति अपने दल का नेता होता है। वह जिस दल का नेतत्व करता है उसका प्रमुख प्रवक्ता होता है। दलीय नेता के रूप मे उसे व्यापक अधिकार प्राप्त होते है तथा उसकी स्थित काफी हढ होती है। प्रो आग (Deg) ने इस स्थित को विशेष मा यता दी है। निर्वाचन के परवात वह अपने दल की घोषित नीति एव कायपम की फ्रिया वित करने के लिए प्रयत्मदोल रहता है तथा अपने दल से घनिष्ठ सनय कताय रखता है। राष्ट्रपति के रूप म उसके पास व्यापक अधिकार होते हैं जिनसे वह लाखो व्यक्तिया को लाम पहुँचाकर उपकृत कर सकता है। उसके द्वारा हुजारो निमुक्तियों की आती हैं, अत दल मे उसकी स्थिति के द्वीय हो आती है। दाइ दल का अनुगमन नहीं करता अधितु यथाय म उसकी नेतृत्व करता है। राष्ट्रपति टापट का कथन था नि "राष्ट्रपति दल का नेता है। उसके लिए दल की नीतिया का परिवार करना सम्भव नहीं है।"

प्रारम्म मे राष्ट्रपति बनीय व्यक्ति नहीं होता या। राष्ट्रपति वास्मितन विस्तान स्थाक्ति में। लेकिन राजनीतिक दला के उदय के पश्चात विस्तपकर राष्ट्रपति वष्टरलं के समय से राष्ट्रपति वलीय आधार पर निर्वाचित होने तमे हैं। दलीय वाधिल एए पित के प्रमुख कनव्य वन गये हैं। उसकी दलीय व्यक्ति न मविधान प्रदत्त अधिकार को अधिक सक्षक्त बना दिया है। उपने वलीय विचारों के समयन में से ही अपने वलीय विचारों के समयन में से ही अपने वलीय विचारों के समयन में से ही सम्बाधित अपने प्रपाद को वर्ष अधिकारत अपने प्रपाद को वर्ष स्थाक्त बना पर स्थान करता है। अपने दलीय प्रमाद को वर्ष स्थान करता है। अपने दलीय समायन से दलीय कायनम एवं नीतियों के विचार करता है।

सूरवाकत—संयुक्त राज्य जयेन्का का राष्ट्रपति केवल अमेरिका गणराज्य की कायपानिका अध्यक्ष ही नहीं है अपितु वह राज्य का मी मुझल है। राद्यपति सान एक किनेडों के अनुसार राष्ट्रपति ही राज्यपत्यत है। उसका कायपतेन अत्यक्षित विस्तृत है। राज्य के भीपचारिक प्रमुख के रूप म जहे निर्मेण वायर निर्मान पढ़ते है। विधि निर्माण म उसकी रिपात के प्रोम है। अधिकाश विधियों उसके ही द्वारा प्रस्तावित की जाती हैं। विदि निर्माण म उसकी रिपात के प्रोम है। अधिकाश विधियों उसके ही द्वारा प्रस्तावित की जाती हैं। विदेश नीति सम्ब भी महत्वपूण निर्माण वहीं करता है। वह अपने दत का नेता होता है। वह राष्ट्र का प्रतितिधित्य करता है। किसी मी अप वेश के अपयक्ष को अपेश अपन दामित्वा के सम्यक्ष का अपन सामक की अपन वेश के अपयक्ष की अपन स्थापत के सम्यादन म उस क्षाया की आवश्यकता होती है। 'वह केवल सामक ही नहीं अगितु राज्य भी करता है।" राज्यप्यक्ष के औपवारिक वाधित्या म वह विदेशी राजदूता एवं राज्यप्यक्ष का स्वायत करता है। इसके अतिरिक्त छोट वह सामाजिक उत्सवों एवं राज्यप्यक्ष का स्वायत करता है। इसके अतिरिक्त छोट वह सामाजिक उत्सवों एवं राज्यप्यक्ष का निमाता है जो विदिष्य मिन्य मण्डल के स्था म वह विदेशी राजदेश वादि है। औपचार्यक्ष के स्था म वह विदेशी राजदेश वाद है। औपचार्यक्ष के स्था म वह विदेशी राजदेश वाद है। अपित सामित्वा का निमाता है जो विदिष्य मिन्य मण्डल के स्था म वह विदेशी राजदेश वाद है। अपित सामित्वा का सम्यक्ष करता है। विद्या प्रायक्ष का सम्यक्ष करता है। अपित सामित्वा का सम्यक्ष करता है। विद्या प्रायक्ष का सम्यक्ष करता है। विद्या प्रायक्ष करता है। विद्या प्रायक्ष का सम्यक्ष करता है।

हरमन काइनर के अनुसार अमेरिकी नायपासिका—गाट्याति—वी 6 मुख्ये विदोपताएँ हैं। "यह एक निर्मित कायपासिका है लेकिन इसका विकास भी ड्रुआ है, ग्रह एकत कायपासिका है, ग्रहुत या सामृद्धिक नहीं, ग्रह व्यवहार म जनता द्वारा प्रस्ता रीति में विवाचित है, यह नायपासिका से अधिन है, ग्रह नायम स पृथक है, इसरा सुभार नहीं क्या जा सनना असे ही इसकी मरम्मत की जा सके।" अध्यापत क अनु सार, 'अमरिकी राष्ट्रपति राष्ट्र ना सम्मानित मूर्तिमान कर है।" शास्त्रीय एनता में

¹³ Finer op 111 , p 669

⁴ President is a dignified embodiment of the nation '-Brogan, D W, In Introduction to American Politics, p. 273

सुरुद्ध बनानं मे राष्ट्रपति न महत्वपूण भूमिका निमाइ है, फलस्वरूप उसकी शक्तियो का असाधारण विकास हुआ है।

अमेरिको राष्ट्रपति का प्रभाव केवल समुक्त राज्य तक ही सीमित नही है। वह राष्ट्र का तो नतृत्व करता ही है, बातर्राष्ट्रीय राजनीति मंभी उसका विशिष्ट स्यान है। वह अपने व्यक्तित्व एवं नीतिया संपरोक्ष रूप मंसभी देशा की प्रभावित करता है।

लाहकों के अनुसार अमेरिकी राज्यपित की शक्तियों पर प्रतिव व के तीन मुक्य कारण है। प्रयम राज्यपित की सर्वैधानिक स्थिति उसकी शक्तियां पर एक प्रतिव ध है। वह कांग्रेस को नीति का निर्देश मात्र कर सकता है, लिंक्न स्वय कांग्रेस को किसी नीति की उपयोगिता एवं वाह्यीयदा के सम्बय्ध में सचुष्ट नहीं कर सकता । वह कांग्रेस का घरस्य नहीं होता। वह राज्य का मने ही नेतृत्व कर परन्तु कांग्रेस का वह नेता नहीं है। उसके अपने दल का कांग्रेस में बहुमत होने पर भी उसे कांग्रेस का सह्याग प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना पडता है। यह सम्भव है कि जिस कांग्रेस म उसके दल का बहुमत हो वह उसका हो विध्यक अस्वीकार कर दे। वह कांग्रेस म नीति का पुत्रपात कर सकता है नेकिन इसके पश्चात उसका उस पर कोई नियानण नहीं होता।

हितोस, 1789 ई को परिस्थितिया में निर्मित बमेरिको सविधान तत्कालीन अमेरिकी समाज की इस प्रकृत्ति को परिलक्षित करता है कि उन्ह बक्तिशाली शासन की आवश्यकता नहीं थीं। घांचतछाली कायपालिका का तात्पय है याधिगटन (राज पानी) का अधिक हस्तोष । अधिक हस्ताेश का अब उस विश्वसस का हिला देना है जो ब्यापारी वन का आधार होता है। यही नारण है कि अमेरिकी समाज पाक्तिशाली राष्ट्रपति के पश्चत वश्चात बहुधा कमजोर राष्ट्रपति को पस ब करता है, विदोषकर एसे राष्ट्रपति को पस व करता है, विदोषकर एसे राष्ट्रपति सो विष्टों कि नियायण की गीति का परित्याग कर विया हो।

राजनीतिक सत्ता पर अमरिकी ब्यापारी वग के बढ़ते हुए आधिपत्य के विरुद्ध सावजनिक अस तोप सित्तवानी कायपालिका के विरुद्ध तीसरा कारण है। इसके अितरिक्त सिक्तवों का विभाजन, सासतीय तिया न्यारा व्यवस्था की स्थापना के प्रति सादेह नजीन करों का व्यवसाय पर विपरीत प्रनाव तथा सास्कृतिक परम्पराएँ साक्ति सादेह नजीन करों का व्यवसाय पर विपरीत प्रनाव तथा सास्कृतिक परम्पराएँ साम्य साला राट्युरित की धारणा के विरुद्ध अप कारण हैं। सास्कृतिक परम्पराएँ साम्य के सम्य घो को निर्पादित करती हैं। अमरिको सविधान एक कृषिप्रधान समाय के सिर्ण निर्माद कुम या वाज का स्थाप प्रमान है। उन समय हिप प्रपान समाज म वतमान औदोनिक समाज की समस्याजा को करना तक नहीं थो। आज राष्ट्रपति की समस्याएँ स्वया मित्र हैं। इस परिवर्तित स्थिति में अमेरिको जनता यह सममने म असमप रही है कि राष्ट्रपति राजनीतिक महराब की आधारितता है। सास्कों के

अनुसार कविस की इच्छात्रा न मवादित राष्ट्रपति अथाह समुद्र म एक ऐन नाकि के समान हे जा पूर्ण निराम के साथ जाग नहीं बढ़ सकता । " सब्द्रपति का एक कार गाल उस अपन विचारा को कियाजित करों के लिए पर्याप्त समय प्रदान नहीं करते है। जहाँ सबद्यक्तिमान एव सवस्यापन अमेरिकी सर्वोच्च पायालय अमेरिकी राष्ट्र पति पर एक निय त्रण है वहाँ व्यवस्थापिका एव प्रशासन स पूज सहयोग का अभाव राष्ट्रवति को अपने दायित्व ने पूज सम्पादन में एक बडी बाधा है। स्मरणीय है गए पति टापट न राष्ट्रपति व वायनाल को 6 या 7 वय करन तथा उसक पुननिवादन सी सिफारिश की थी। सक्ट-काल म दास्तिशासी राष्ट्रपतिया का निर्वाचन किया गया है तथा राष्ट्र एव कांग्रेस न उनका नेतृत्व स्वीकार किया है। उदाहरण के लिए, तिसन एवं विस्तन ने बम यह तानाशाहा की चिक्तियों का प्रयोग किया था। वे सक्ट-कात व ही पदारुव हुए थे सबिन सकट की समाप्ति के परचात कांग्रेस ने सप्टबति की शक्तिया यो सीमित करने का प्रयत्न किया है। कविस ने राष्ट्रपति वित्सन द्वारा स्वीकृत वार्साई सिंध को अस्वीकार कर दिया या। कर्कालन ही कजवेल्ड ने प्रथम बार राष्ट्र पनि बनने (1932 ई) क तुरत बाद कांग्रेस के दोनी सदनी का निर्देशन किया था। लेकिन 1933 ई की गरियों न परचात ही कांग्रेस ने राष्ट्रपति की राह्त को चनीती हेना प्रारम्भ कर दिया था।

सिषपान निर्मात राष्ट्रपति को इतना सक्तियाली नहीं बनानर पाइने थे। सस्तव म उसकी सिक्तियों का निरंतर विकास हुआ है। इसके दिग्न कारण हैं प्रयम्, राष्ट्रपति का निवासन व्यवहारत अत्यक्ष हो गाम है। यह जनता का प्रयुक्त नेता तथा देश की प्रमुक्त कामपालिका एव शासन का प्रमुक्त प्रवक्ता है। दित्रीय, नधीय सासन दो सिक्तियों में वृद्धि। तृतीय कांग्रेस की असफलता। वृत्य, दक्त का प्रमुक्त नेता होने के वारण भी राष्ट्रपति की शक्ति में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, वतमान अत्राष्ट्रीय विवादि के कारण भी राष्ट्रपति के पद का महत्व वढा है। अत्यक्ति सक्ति-सम्पन होने में कारण, सीमन के अनुसार, राष्ट्रपति तृतीय सदन वन यया है। वह उन मामला भ भो जी परम्परागत कल में व्यवस्थापिका का क्षेत्र है कांग्रेस के विवरीत मत रक्षता है

राष्ट्रपति की अस्ति-सम्पाता के सम्बाध में एक कटु सत्य यह है कि उसको सिक्त एवं क्षमाना उस पद के धारण करने वाले व्यक्ति पर निभर करती है। विलस्त का करने था कि राष्ट्रपति का पद एक समय में कुछ तो दूसरे में कुछ रहा है। इसका कारण राष्ट्रपति की विभिन्न व्यक्तित्व एवं तत्कालीन निम्न मिन्न परिस्थितियाँ है। एक सफ्त एक सम्बाध के स्वति व्यक्तित्व की एक सम्बाध स्वति के स्वति व्यक्तित्व की स्वति के स्वति के स्वति व्यक्तित्व की स्वति व्यक्तित्व की स्वति के स्वति स्वत

¹⁵ Lasht The American Presidency, 1943 p 30

रोक्त सद्यक्त राष्ट्रपति अमेरिकी इतिहास के गुग-निर्माता रहे हैं एव उ होने काग्रेस का नेतृत्व किया है, तो दूसरी तरफ हूवर जसे कमओर राष्ट्रपति थे जि होने काग्रेस का विनम्रतापूवक अनुगमन किया था। 1836 ई से 1861 ई एव 1865 ई से 1898 ई तक का काल विशेष रूप से कमओर राष्ट्रपतिया का काल था।

सास्की के अनुसार, "अमेरिकी राष्ट्रपति के काय व्यापक है, वह राज्य का औपचारिक अव्यक्ष है, विधि निर्माण का व्यापक कोत है, सभी कायपालक निणयो का अतिम लोत है एव देश की विदेश नीति का अधिकृत प्रवक्ता है।"16

राष्ट्रपति एव उसका मन्त्रिमण्डल

अमेरिकी मा त्रमण्डल प्रतिनिधि शासन की परम्परागत मा त्रमण्डलीय व्यवस्था से सबधा मित है। अमेरिकी सबिधान में केवल यह व्यवस्था है कि "कायपालिका विमागो से सम्बर्धित मामला मे राष्ट्रपति लिखित परामश प्राप्त कर सकता है। "17 इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति वाद्यियटन के समय की कछ घटनाओं ने अमेरिका की वत-मान मित्रमण्डलीय व्यवस्था के लिए भनिका तथार की थी। यद्यपि सर्विधान निर्माता कायपालिका द्वारा परामश की आवश्यकता को अनुभव करते थे परात इस सम्बाध मे उन्होंने कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की । सीनेट को नियुक्तिया एव सिंघया के सदम म अनुसमयन की शक्ति देकर सर्विधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति को शासन में परामश की आवश्यकता की पूर्ति की थी। राष्ट्रपति वाशियटन ने अमेरिका के मूल निवा-सियो के विषय में सीनेट स परामध माना था क्योंकि वार्शिगटन की धारणा थी कि सीनेट उपनिवेशों के उच्च सदनों की भाँति एक परामश्रदायी सदन के रूप म काय करेगा। लेकिन सीनेट ने राष्ट्रपति बाशियटन के आग्रह की उपेक्षा कर दी। इसके पश्चात ब्रिटिश एव औपनिवेशिक यायालयो का अनुगमन करते हुए राष्ट्रपति न सर्वोच्च "यायालम से परामशदायी निणय के रूप म सहायता प्राप्त करने की चेप्टा की । परातु सर्वोच्च न्यायालय ने भी कोई परामश देना अस्वीकार कर दिया । फल-स्वरूप राष्ट्रपति वाशिगटन अपने दस प्रशासनिक विभागा के प्रमुख अधिकारिया के सम्भेलन बुलाने एव उनसे परामश करने लगे थ । प्रारम्य म विमागाध्यक्षों के इस प्रकार के सम्मेलन अनियमित होते थे. लेकिन 1793 ई म विदेशी आजनाण के प्राप के कारण राष्ट्रपति ने प्रमुख अधिकारिया की नियमित बैठकें बुलाना प्रारम्म कर दिया । उसी समय से विभागाध्यक्षा के सम्मेलन को मित्रमण्डल की सना दी गयी है।

^{16 &#}x27;The range of the President's function in enormous He is ceremonial head of the State He is a vital source of legislative suggestion. He is the final source of all executive decisions. He is the authoritative exponent of the nation sforeign policy."—Lasks. The American Presidency, 1943 p. 37.

¹⁷ Article II, Section 2 Clause (1)

666 अर्धान वासात प्र

आज रिश्रमण्डल अमेरिको सासनतात्र का एर अनिवास एव अमिन्न अन कर गर्वा है। इसना मिष्पार म बही उल्लेख नहीं है। इसका विशास 170 वर्षों म हुनाई। अस यह एक अभोषाशास्कि सस्या है जिसका विशास मुनिधा एवं परम्पत ना परिणाम है।

सगठन

1789 ई म वजल तीन-राज्य, सुरक्षा तथा नापागार-प्रशासनिक विमार थ, सेकिन आज इनकी सख्या दस है। उपरोक्त तीना विभाग क अनिरिक्त रोप सात विभाग हैं व्यापार, श्रम, जान्तरिक मामला सम्ब थी, कृषि, डाक, याम एव शिक्षी तथा जन कल्याण । मित्रमण्डल वे सदस्या की नियुक्ति राय्ट्रपति द्वारा सीनेट क 2/3 बहमत ने समयन से की जाती है। सामा यत राष्ट्रपति द्वारा जा नाम प्रस्तावित किय जात हैं उह सीनट स्वीकृति प्रदान कर देती है। लेकिन राष्ट्रपति इनका नियक्ति बरत समय अनेव बाला को ध्यान म रखता है, जैसे-विभिन्न क्षेत्रों के मौगी लिक, आधिक एव धार्मिक हित, निर्वाचन य सहयोग देन वाले व्यक्ति एव वग, व्यक्ति गत मित्रता एव दलीय सहयोग । वह इन सभी तत्वा को मित्रमण्डल म शामिल करने का प्रयास करता है। 1795 ई से विभि न राष्ट्रपतिया ने मित्रमण्डल म अधिकाशत अपन ही दल क सदस्यों को नियुक्त किया है। स्मरणीय है कि राष्ट्रपति वाशिगटन न श्री जेफरसन का विदेश सचिव और हैमिल्टन को विस्त सचिव नियुक्त किया था पर तू जनम मतभेद उत्पान हो गये थे । फलस्वरूप यह अनुभद किया गया कि विभागाध्यक्ष ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो राजशीतिक मामला म मतभेद न रखत हा। यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति अपने दल के सदस्य का ही विमागाध्यक्षी के रूप म नियुक्त करे। उदाहरणाय, राष्ट्रपति रूजवेल्ट न 1941 ई म अपने मित्रमण्डल म रिपब्लिकन दल के सदस्या-हैराल्ड नीवस, हेनरी वालास एव एच एल स्टिमसन-को नियक्त किया था । 1928 ई म राप्ट्रपति कृतिज न यायाधीश स्टोन (Justice Stone) की अटोनीं जनरल नियुक्त किया था। थियोडार रूजनेस्ट एव टाफ्ट दानो ने डेमाजेटिक दल के एक एक सदस्य का अपने मित्रमण्डल म नियुक्त किया था। फ्रेक्लिन डी रूपवेल्ट ने रिपब्लिकन दल के सदस्य स्टिमसन (Stimson) को विदेश-सचिव एवं फाक कान (Frank Knox) को नौसना-सचिव नियुक्त किया था । सध्द्रपति जान एक केनेडी न रिपलिकन दल के सल्स्य डीन रस्क को विदेश सचिव बनाय रखा था। स्मरणीय है कि डीन रस्क को जॉन फोस्टर डलेस की मृत्यु के पश्चात राष्ट्रपति केनेडी के पूर्वगामी राष्ट्रपति आइजनहोवर ने विदेश-सचिव नियुक्त किया था। सिवया नी नियक्ति करते समय राष्ट्रपति ज य व्यक्तिया से भी परामश कर सकता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति विल्सन ने अपने सचिव ट्यूमलटी (Tumulty) स रिसी व्यक्ति का नाम मित्रमण्डल की सदस्यता वे लिए प्रस्तावित वरने को कहा था। ट्यमलटी ने

राष्ट्रपति विल्सन को लिण्डसे गैरीसन (Lindsey Garrison) का नाम प्रस्तावित किया जिससे उसके बहुत कम सम्ब व थे। राष्ट्रपति विल्सन न गैरीसन को अपने किया। जिससे उसके बहुत कम सन्य य न राष्ट्रपति विस्तान का गैरीसन से कोई पूर्व परिचय नहीं या। यह भी आवश्यक नहीं कि मिनिमण्डल के सदस्यों को राज्नीतिक अनुभव हो। राष्ट्रपति हुवर ने राजनीतिक जीवन से पूण अनविज्ञ नात्स आदम (Charles Adam) को नीसना सचिव नियुक्त किया था। अमेरिकी राप्ट्रपति को अपने सचिवो को नियुक्त करते समय उन सब बातो का ज्यान नही रखना पटता है जो ब्रिटिश प्रधानमात्री रखता है । ब्रिटिश प्रधानमात्री के मित्रमण्डल के सदस्य उसके सहयोगी हाते है । स्मरणीय है, अमेरिकी राष्ट्रपति अपने सहयोगियों की एक टीम का चयन नहीं करता है । यह सम्मव है कि वह जिनको चुनता है उन्हें वह जानता भी न हो। कम से कम यह तो निश्चित ही है कि नियुक्त मित्रयामे से बुख तो एक दूसरे को निश्चय ही नही जानते। लास्की के अनुसार मित्रमण्डल का चुनाव करते समय वह कम से कम एक या दो ऐसे "पक्तियो ना चयन अवश्य करता है जिनका काग्रेस म प्रमाव होता है। मि त्रमण्डल मे एक सदस्य अनिवायत दल की देखमाल एव व्यवस्था करने वाला होता है। राष्ट्-पति देश के विभि न क्षेत्रो एव धार्मिक तत्वा का भी मि तमण्डल मे प्रतिनिधित्व देन का प्रयस्त करता है। वह यहूदी समाज के मतो को प्राप्त करन के लिए एक यहूदी सदस्य को अवश्य नियुक्त करता है। इसके अतिरिक्त, क्षित्रया एवं मजदूर दलों को भी मित्रमण्डल मे प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। मा निमण्डल के सदस्यगण राष्ट्रपति के प्रसाद पयात ही अपने पद पर रहते हैं।

प्रकृति

विमश र रना चाहता हूँ । हर वाल तत्क्षण जनता को नही बतायी जा सक्ती । यह मरा विद्योषाधिकार है कि मैं ही यह निर्पारित करूँ कि क्या कव और कस कहा जायगा। सनी विचार विमय मित्रमण्डल म पूरी तरह स्वत त्रतापूबक होने चाहिए। यदि एसा सम्ब नहीं है तो मेरे लिए सभी योपनीय बाता पर मित्रमण्डल म विचार करना सम्बद नहीं होगा ।"

अमेरिकी मन्त्रिमण्डल के सदस्य राष्ट्रपति की अनुमति से नवीन नीतिर्या

प्रारम्भ गर सकत हैं। मित्रमण्डल के निणय राष्ट्रपति के लिए केवल परामद्य या सलाह के रूप म होते हैं। उहें किसी सामृहिक मण्डल के सयुक्त कार्यों की स्थिति प्रदान नहीं की जा सकती । राष्ट्रपति मित्रमण्डल के निषयों की मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। वह मित्रिया के परामदा को अस्वीकार कर सकता है। यह भी सम्भव है कि वह मित्रियो से परामध ही न कर। सम्भव है कि किसी मंत्री से सहस्वपृण विषय में परामध ही न किया गया हो। निषय करने में मंत्री से अधिक सहायक कोई प्रमावशासी सीनेटर या कांग्रेस का सदस्य हो सकता है। मित्रमण्डल के सदस्य क रूप मे वे कमी कमी राज्यति द्वारा निर्धारित निषयों को ज्यों का त्या स्वीकार कर लेते हैं। राज्य-पति के निगमा को स्थीकार करने के अतिरिक्त उनके समक्ष अन्य कोई विकल्प भी नहीं होता। राष्ट्रपति पर मित्रमण्डल काया उसके बहुमत का निणय व धनकारी नहीं है। राष्ट्रपति लिंकन ने एक बार एक मामला मिनमण्डल के समक्ष उपस्थित किया था। मित्रमण्डल के सातो सदस्यों ने उसका विरोध किया । राष्ट्रपति लिंकन ने इस पर कहा था कि "सात विपक्ष म है लेकिन एक पक्ष मे हैं, अत एक ही की विजय है।"

मि त्रमण्डल के समस्त सदस्यों को राष्ट्रपति की आज्ञा का पालन करना होता है और जो सदस्य ऐसानहीं करते हैं उह मंत्री पद से त्यागपत्र देना पडता है। कोई भी मानी राष्ट्रपति का प्रतिस्पर्दी नहीं हो सकता। राष्ट्रपति विल्सन एवं असके विदेशम नी लेंगसिंग में सतभेदों के उग्र होने पर लेगसिंग को ही स्यागपत्र देना पढा था। राष्ट्रपति विल्सन 1920 ई म अस्वस्य थे। लेंगसिंग ने मित्रमण्डल का वरिष्ठ सदस्य होने के नाते मित्रमण्डल की बैठक बुलाई थी। राष्ट्रपति न लेगीसग के इस कृत्य की मत्सना करते हुए उन्ह लिखा था कि 'नया यह सत्य है कि मरी अस्वस्थता -के दौरान तुमने कायकारी प्रधाना के सम्भलन आयोजित किये हैं ? हमारी सवधानिक व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति (केवल राष्ट्रपति और काग्रेस) को ही सावजनिक मामलों क सम्बाध म कायकारिणी के प्रधाना के विचार जानने का अधिकार है। राप्ट्रपति की सत्ता को इस प्रकार हस्तगत करने क औषित्य का कोई कारण मैं तुम्हारे पत्रों में नहीं पाता हूँ।"

सामको न अमेरिकी पन्त्रिपण्डल की प्रकृति का निम्न शब्दों म व्यक्त किया है "मित्रमण्डल राष्ट्रपति का परामश्रदासा है। वह सहयोगिया की समिति नहीं है जिनके साथ राष्ट्रपति को काय करना पडता हो और जिनकी सहमति पर वह निमर हो । सयुक्त राज्य अमरिका म मन्त्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व का अमाव है। " मिन-मण्डल के प्रति सप्ताह सम्मलन होते हैं जिसम केवल उन्ही प्रश्नो पर विचार-विमश होता है जिन्ह राष्ट्रपति उपस्थित करता है। महत्वपूण विषया का मित्रमण्डल के समक्ष उपस्थित नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति की इच्छा के विपरीत सारे मित्रमण्डल की बात भी नहीं कल सकती है। ऐसा कोई विमाग नहीं है जिसके सीति निर्धारण म राष्ट्रपति का स्थान प्रमुख न हो । वह सभी (भिनयो) ने निणयो का पुनरावेदनीय मायालय है। उसका निषय अन्तिम है। सामृहिक रूप से मिनमण्डल का राष्ट्रपति की मीति राष्ट्र या कथिस पर कोई प्रकाब नहीं होता । कुछ मंत्री निस्स देह राष्ट्रपति को प्रमावित करने म सफल होते हैं लेकिन कभी कोई मित्रमण्डल राष्ट्रपति को नियात्रित नहीं कर सका है। सामा यत मित्रमण्डल के सभी सदस्य यह जानते हैं कि वे राष्ट्रपति की श्रवद्याया म ही अपने पद पर रह सकते हैं। मान्नी की स्थिति राष्ट्र-पति की इच्छा पर निमर करती है। 19 स्पष्ट है, अमेरिकी केविनेट ब्रिटिश अर्थी म मित्रमण्डल नहीं है । 20

मिनमण्डल तथा राष्ट्रपति ने सम्बाध बहुत कुछ वोनो के व्यक्तिस्वो पर निमर करते हैं। फलस्वरूप विधिन समयो से उनके सम्बाध से अस्तर रहा है। बुत्तनात (Buchman) एव हाडिल (Hardmee) वसे कपनो राष्ट्रपतियों ने अपने भी भारतक (Buchman) एव हाडिल (Hardmee) वसे कपनो राष्ट्रपतियों ने अपने भी भारतक के सदस्यों को बहुत अधिक छूट वी थी। इसके परिणाम कभी कभी हानिकारिक मी होते हैं। यक्तिशाली राष्ट्रपति इसके विपरीत, सम्बद्ध है, किसी एवं सदस्य पर बहुत अधिक विवस्ता हो। किसी भी मंत्री के तिए इह निक्सी राष्ट्रपति को निर्मान्त करता वस्मय हाता है। कुछ राष्ट्रपति अनिमन्त्रक कर वस्स्या को सहयोगी मानते थे तो दूसरे अधीनस्य कमचारी। कुछ शास्ट्रपति योग्य एवं झमतायुक्त व्यक्तियां को मंत्री पर देने मंत्र विवस्ता करते थे तो कुछ सान्द्रपति को निर्देशन एवं सम्तराकार्यकमान स्नात मानते थे। राष्ट्रपति जैनसन के वो वर्षों तक मंत्रिमण्डक को वीई सम्मेलन ही नहीं कुलाया था। वे उत्ते एक कष्टमाध्य दासित्व मानते थे। एष्ट्र जैनसन के अपने व्यक्तियां मानते थे। एष्ट्र जैनसन के अपने व्यक्तियां मानते थे। प्रकृत जैनसन के अपने व्यक्तियां मानते थे। एष्ट्र जैनसन के अपने व्यक्तियां मानते थे। विद्रापति वीक्तियां मानते थे। त्राप्ट्रपति वीक्तियां मानते थे। प्रकृत जैनसन के अपने व्यक्तियां मानते थे। विद्रापति वीक्तियां मानते थे। प्रकृत जैनसन के अपने व्यक्तियां मानते थे। प्रकृत जैनसन के अपने व्यक्तियां मानते थे। विद्रापति वीक्तियां मानते थे। विद्रापति वीक्तियां मानते थे। विद्रापति वीक्तियां मानते थे। स्वर्त्ता विद्रापति विद्रापति वीक्तियां मानते थे। स्वर्ता विद्रापति विद्रापति वीक्तियां मानते थे। स्वर्तापति विद्रापति विद्राप

¹⁸ The Cabinet is a body of advisors to the Freatdent, it is not a Council of colleagues with whom he has to work and upon whose approval he depends. In United States, collective cabinet responsibility does not exist. "—Laski. of at. p. 82.

¹⁹ Ibid pp 82 97

^{20 &}quot;American Cabinet is not a Government, as is the British"
—Bailey, S D Aspects of American Government, p 30

चिमदा परना चाहता हूँ। हर बात तत्थण जनता को नहीं बतायों जा सनती। यह मच विषेपाधिकार है नि में ही यह निर्धारित करूँ कि क्या कब और को कहा जायगा। सभी विचार विमय मिनमण्डल से पूरी तरह क्वत प्रतापूषक होन चाहिए। यदि ऐसा सम्ब नहीं है सो मरे तिए सभी योपनीय बाता पर यित्रमण्डल से विचार करना सम्ब नहीं होया।"

अमेरिकी मित्रिमण्डल के सदस्य राष्ट्रपति की अनुमति से नदीन नीतियाँ प्रारम्भ कर सकत हैं।

मिनमण्डल के निणय राष्ट्रपति के लिए केवल परामदा या सलाह के रूप में होते हैं। उन्हें विसी सामूहिक मण्डल के समुक्त कार्यों की स्थित प्रवाम नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति मिनमण्डल के तिण्यों को मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। वह मिन्नया के परामदा को अस्वोकार कर सकता है। यह यो सम्मव है कि वह मिन्नया के परामदा को अस्वोकार कर सकता है। यह यो सम्मव है कि वह मिन्नया के परामदा हो। निजय करने में मंत्री से अधिक सहाव को प्रमावधानी सीनटर या क्षेत्र का सदस्य हो सकता है। यो निजय करने में मंत्री से अधिक सहाव को प्रमावधानी सीनटर या क्षेत्र का सदस्य हो सकता है। यो निजय करने में मंत्री से अधिक सहाव को में प्रमावधानी कीनटर या क्षेत्र का सदस्य हो सकता है। यो निजय करने से में के का राष्ट्रपति द्वारा निजयित निणयों को ज्यों वा त्यों क्षेत्र कर तेते हैं। राष्ट्रपति कि निणयों को स्थीकार करने के अतिरिक्त उनके समक्ष अप कोई विकल्प भी नहीं होता। राष्ट्रपति विकल ने एक बार एक मानना मिनमण्डल के समक्ष उपस्थित किया। पाट्रपति किकन ने एक बार एक मानना मिनमण्डल के समक्ष उपस्थित किया। पाट्रपति लिकन ने इस पर कहा या कि 'शात विवक्ष सं है लेकिन एक एक सं है, अत एक ही की विजय है।'

या त्रमण्डल के समस्त सदस्यों को राष्ट्रपति की आज का पालन करना होता है और जो सदस्य ऐसा नहीं करते हैं उहें गं की पद से त्यायपत्र देना पढता है। कीई जी गं नी राष्ट्रपति का प्रतिस्पर्धीं नहीं ही सकता। राष्ट्रपति विस्तत एवं उसके विदेशमंत्री लेगीसिंग में मतंत्रेयों के उब होने पर सेमिंग का ही। त्यायपत्र देता पड़ा या। राष्ट्रपति विस्तत 1920 ई म व्यवस्थं थे। लेगिसा ने मं निमण्डल का वरिष्ठ सदस्य हीने के नाते मिन्त्रमण्डल की बैठक बुलाई थी। राष्ट्रपति न सेनीसा क इस इस्त की मत्साना करते हुए उह लिखा था कि 'क्या यह सत्य है कि मेरी अस्वस्थता के दौरात तुमन कायकारी प्रयाना के सम्मत्त वायोजित किय है हि मोरी अस्वस्थता के दौरात तुमन कायकारी प्रयाना के सम्मत्त वायोजित किय है हि मोरी अस्वस्थता के दौरात तुमन कायकारी प्रयाना के सम्मत्त वायोजित किय है हि मोरी अस्वस्थता के स्वारा के समस्य म कायकारियों के प्रयाना के विचार जानने का अधिकार है। राष्ट्रपति की सता को इस प्रकार हस्तयत करने के वीचित्य का कोई कारण में तुम्हार पर्यो म नहीं पाता है।"

लास्की न अमेरिकी मि जिमण्डल की प्रकृति को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है "मित्रमण्डल राष्ट्रपति का परामर्शदाता है। वह सहयोगियो की समिति नहीं है जिनके साथ राष्ट्रपति को काय करना पडता हो और जिनकी सहमति पर वह निमर हो। सयक्त राज्य अमरिका म मित्रमण्डलीय उत्तरदायित्व का अभाव है। '18 मित-मण्डल के प्रति सप्ताह सम्मेलन होते हैं जिसम केवल उ ही प्रश्नो पर विचार विमश होता है जिह राष्ट्रपति उपस्थित करता है। महत्वपूण विषयो को मित्रमण्डल के समक्ष उपस्थित नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति की इच्छा के विपरीत सारे मित्रमण्डल की बात भी नहीं चल सकती है। ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसके नीति निर्धारण म राष्ट्रपति का स्थान प्रमुख न हो । वह सभी (मन्त्रियो) के निणयो का पुनरावेदनीय 'यायालय है। उसका निगय अन्तिम है। सामूहिक रूप से मित्रमण्डल का राष्ट्रपति की साति राष्ट या काग्रेस पर कोई प्रभाव नहीं होता । कुछ मात्री निस्स देह राष्ट्रपति को प्रमावित करने में सफल होते हैं लेकिन कभी कोई मित्रमण्डल राष्ट्रपति को नियत्रित नहीं कर सका है। सामायत मित्रमण्डल के सभी सदस्य यह जानते हैं कि वे राष्ट्रवृति की छत्रछाया मे ही अपने पद पर रह सकते है। मात्री की स्थिति राष्ट्र-पति की इच्छा पर निमर करती है। 1º स्पष्ट है, अमेरिकी केबिनेट ब्रिटिश अर्थों मे मित्रमण्डल नहीं है।²⁰

मित्रमण्डल तथा राष्ट्रपति के सम्बाध बहुत कुछ दोना के व्यक्तित्वा पर निभर करते हैं। फलस्वरूप विभिन्न समयों में उनके सम्बाधी में अतर रहा है। बूचनान (Buchnnan) एव हाडिज (Hardinge) जसे कमजोर राष्ट्रपतियो नै अपने मित्रमण्डल के सदस्यों को बहुत अधिक छट दी थी। इसके परिणाम कभी कभी हानिकारिक भी होते है। शक्तिशाली राष्ट्रपति इसके विपरीत, सम्मव है, किसी एक सदस्य पर वहत अधिक विश्वास करता हो। किसी भी मानी के लिए हढ निश्चयी राष्ट्रपति को नियानित करना असम्मव होता है। कुछ राष्ट्रपति मित्रमण्डल के सदस्यों को सहयोगी मानते थे तो दूसरे अधीनस्य कमचारी । कुछ राष्ट्रपति योग्य एव क्षमतायुक्त व्यक्तियो को मात्री पद देने मे विश्वास करते ये तो कुछ मानी राष्ट्रपति को निर्देशन एव समताका एकमात्र स्रोत मानते थे। राष्ट्रपति जैनसन ने दो वर्षों तक मित्रमण्डल का कोई सम्मेलन ही नही वूलाया था । वे उसे एक कप्टसाध्य दायित्व मानते थे । एण्डू जैक्सन के अपने व्यक्ति-गत सलाहकार ये जि ह 'पाकशाला मित्रमण्डल' (Kitchen Cabinet) की सना दी

^{18 &#}x27;The Cabinet is a body of advisors to the President, it is not a Council of colleagues with whom he has to work and upon whose approval he depends In United States, collective cabi net responsibility does not exist '-Laski op at, p 82 19 Ibid pp 82 97

²⁰

[&]quot;American Cabinet is not a Government, as is the British " -Bailey, S D Aspects of American Government, p 30

670 | आयतिन सासनत न

गयी थी। इस 'पाकदाला मित्रमण्डल क अउक व्यक्तिगत मित्र मित्रमण्डल ना अपक्षा राष्ट्रपति वर अधिव प्रमाव रखते थे। राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डी रूजवत्ट क बार म भी यही बात सत्य ह । व अपने व्यक्तियत मित्रा स बिन्ह 'Brains Trust' नहा जाता था, प्राय परामदा करत थ ।21 राष्ट्रपति जनरल ग्राण्ट मित्रमण्डल का सहायक (Second Lieutenant) मात्र समनता या । राष्ट्रपति बलीवलण्ड इसन विष रीत मित्रमण्यस व सदस्या व विजारा को विशेष महत्व प्रदान करत थ । बुक्रो विस्तान एवं फेरुसिन डी रूजवेल्ट ने कभी भी अपने मित्रया की अपने विस्तास में नहीं लिया। राष्ट्रपति विल्सन ने जायुद्ध सादेग दियाया वह उन्होन अपने मिन मण्डल को सराधन की सम्मावना के कारण दिखाया तक नहीं था। फकलिन रूजवेस्ट क समय म भी मित्रमण्डल का विद्येष महत्व नहीं रहा। विल्सन एव फेकलिन डी रूप-वेस्ट के सम्बाध म यह कहा जाता है कि उनके सचिवा को ता बहुत सी सुचनाए समाचार पत्रों से ही पात होती थी। थियोडोर रूजवल्ट पहले निणय कर लेत थे एव मित्रमण्डल को उनकी सचना मात्र देत थे। फकलिन कजवेल्ट के यद्यमात्री स्टिम सन का कथन था वि "मि त्रियों का उपयोग बठका के समाप्त होन के पश्चात राष्ट्र पति में व्यक्तिगत वार्ता के लिए खाइट हाउस जाना मर रह गया है। राष्ट्रपति दू मैन एव विदेश मात्री डीन एचिसन क मध्य यदि सम्बाध अच्छे ये तो इसका नारण यह या कि डीन एचिसन राष्ट्रपति के अनुकृत परामशदाता एवं नीतियों को निया-वित करन वाले व्यक्ति थे।" राष्ट्रपति आइजनहोवर एव विदेश मानी जॉन फोस्टर इतिस क सम्बन्ध सबया मिन थे। राष्ट्रपति आइजनहोवर । उत्तेस को आवश्यक अधिकार प्रदान कर रखे थे तथा डलेस की अवक तत्परता एव उद्योग ने उसे अ तर्राष्ट्रीय क्षेत्र म सर्वाधिक महत्वपूण व्यक्तिव बना दिया था। उसके किसी अय प्रवाधिकारी को ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं हुई था। 3 अमरिकी मन्त्रिमण्डल हि मिन है। ब्रिटिश

तथा सभी के प्रति उत्तरदायां हाव है। मित्रमण्टलीय एव सामूहिक उ 21 fati नारा योग्य ,

मीजमण्डल के सदस्य सावजनि

के सदस्य होते हैं, उन्हें जनता व

तरहं ८

सकीणत 22 Max Bei

Max Belu

ैन है। व एक ही दल

द के सदस्य होते हैं

ेपद पर रहते.

आधार है। ब्रिटिश प्रधानम त्री सहयोगियों की टीम का नता होता है। वह समक्क्षो म प्रथम है। इसके विषरीत, जमरिकी मी त्रमण्डल क सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त तिय जाते हैं। वे उसके परामशदाता होत है। राष्ट्रपत्ति के व अधीनस्य कमचारी है। जनके परामरा एव विचारा को मानना या न मानना राष्ट्रपति पर निभर करता है। यह क्षावश्यक नहीं है कि वे सब एक ही राजनीतिक विचारधारा के सदस्य हा । जमरिकी राष्ट्रपति की शक्ति एव व्यक्तित्व ने उनकी सम्पूण प्रतिमा आच्छादित रहती है। मिन-मण्डल के निषम राष्ट्रवित के लिए परामश मात्र है। अमेरिकी व्यवस्था म मिन सण्डलीय सामृहिक उत्तरदायित्व का पूण अमाव है। सचिवनण काँग्रेस के सदस्य नहीं होते । मन्त्री पद अमरिकी राजनीतिक जीवन स अस्यायी अवकाण माना जाता है। उनकी तुलना म सीनेटर की स्थिति अधिक प्रमावशाली एवं हव होती है। बहुत से राष्ट्रपति अपने मित्रवा से परामध करन की अपेक्षा सीनटरा से परामध करता अधिक लामप्रद समभत थे। अमेरिको मात्रीगण अपन पद सं त्यागपत्र देकर अपनी स्थिति को यहा नहीं सकत, अपित त्यागपन के साथ उनके राजनीतिक जीवन का अन्त हो जाता है। अग्रेरिकी मी नमण्डल के सदस्य विदिश मन्निया का मौति काग्रेस के नेतानहीं हाते और न ब्रिटिश में त्रमण्डल की मालि वह नीति का निर्माण ही करते है । राष्ट्रपति मिनया का स्वामी है और उन सब में सर्वोच्च है। अमे-रिका में बिटन की भानि मि तमण्डल को शासन की असफलवा के लिए दोपी नही ठहराया जाता अपित राष्ट्रपति ही प्रशासनिक असफलता के लिए उत्तरदायी हाता है। ब्रिटिश मित्रया की तुलना में अमेरिकी व शी का स्थान निस्म देह नीचा है। राष्ट्रपति सम्प्रण दश का प्रतीक है। अपने कायकाल में वह अ'य किसी प्रतिस्पर्धी अस्तित्व की स्वीकार नहीं करता है। उसके स्वर की तुलना म उसके म जी की आवाज मुनमुनाहट मात्र होती है जिसे सुना भी जा सकता है और नहीं भी।

मिनिमण्डल की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए राष्ट्रपति टाफ्ट (Taft) का निम्न क्यम महत्वपूण है "मिनिमण्डल राष्ट्रपति की कृति है। यह एक अविधिक एवं असविधानिक निकास है। यह परम्परा पर आधारित है। यह राष्ट्रपति इसे समाप्त करना चाहे तो कर सकता है।" वै तिका 25व सर्वधानिक सरोधन (1967 ई) के पारित होने के काला है।" वै तिका 25व सर्वधानिक सरोधन वाइ सामिण को सर्वधानिक सरोधन समाप्त हो सामिण को सर्वधानिक सरोधन सामिण के प्रारत होने के स्वीपन हारा मिनिमण्डल को कायपालिका विमाना के प्रमुख अधिकारिया के निकास का नजा दी सर्वी है।"

^{24 &}quot;Cabinet is a mere creation of the President's will, it is an extra statutory and extra constitutional body. It exists only by custom. If the President desired to dispense with it, he could do so "—Taft W H. Our Chief Magistrale and this Powers, p. 30

^{25 25}व संशोधन द्वारा यह व्यवस्था भी की मयी है कि राष्ट्रपति की मत्यु या मानसिक

गयी थी। इस 'पाकशाला मित्रमण्डल' के उनके व्यक्तिगत मित्र मित्रमण्डल की अपक्षा राष्ट्रपति पर अधिक प्रमाव रखते थे। राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डी रूजवेल्ट के वार म भी यही बात सत्य है। वे अपने व्यक्तिगत मित्रो से जिन्ह Brains Trust' कहा जाता था, प्राय परामश्च करते थे। राष्ट्रपति जनरल ग्राष्ट मित्रमण्डल को सहायक (Second Lieutenant) मात्र समभता था । राष्ट्रपति क्लीवलण्ड इसके विष रीत मिन्नमण्डल के सदस्यों के विचारों की विशेष महत्व प्रदान करते थे। बुडरो विल्सन एवं फ्रेकलिन डी रूजवेल्ट ने कभी भी अपने मन्त्रियों की अपने विश्वास मे नहीं लिया। राष्ट्रपति विल्सन ने जो युद्ध संदेश दिया था वह उन्होन अपने मिन मण्डल को सशोधन की सम्मावना के कारण दिखाया तक नही था। फ्रेंकलिन रूजवेल्ट के समय मंभी मित्रमण्डल का विशेष महत्व नहीं रहा! विल्सन एवं फ़ेंकलिन डी रूज वल्ट के सम्बाध म यह कहा जाता है कि उनके सचिवों को तो बहुत सी सूचनाए समाचार-पत्रों से ही ज्ञात होती थी। थियोडोर रूजवेल्ट पहले निजय कर नेते थे एव मिनमण्डल को उनकी सुचना मान देत था। फ्रेकलिन रूजवेल्ट के युद्धमात्री स्टिम-सन का कथन था कि "मि त्रयो का उपयोग वठका के समाप्त होन के पश्चात राष्ट पति से व्यक्तिगत वार्ता के लिए ह्याइट हाउस जाना भर रह गया है। राष्ट्रपति ट्रमैन एव विदेश मात्री डीन एचिसन के मध्य यदि सम्बाध अच्छे थ तो इसका कारण यह था कि डीन एचिसन राष्ट्रपति के अनुकूल परामशदाता एव नीतिया की किया-वित करन वाले व्यक्ति थे।" ^३ राष्ट्रपति आइजनहोवर एव विदेश मात्री जान फोस्टर डलेस के सम्बाध सबया भिन थे। राष्ट्रपति आइजनहोवर न डलेस को आवश्यक अधिकार प्रदान कर रखे वे तथा डलेस की अथक तत्परता एव उद्योग ने उस अन्तर्राप्टीय क्षेत्र म सर्वाधिक महत्वपूण व्यक्तित्व बना दिया था। उसके किसी अय पूर्वाधिकारी को ऐसी स्थिति प्राप्त नही हुई थी। ³

अमेरिकी मीत्रमण्डल बिटिस मित्रमण्डल स पूणरुपेण भिन है। विटिस मित्रमण्डल के सदस्य सावजनिक जीवन के सित्रिय राजनीतिज्ञ हात है। व एक ही दल के सदस्य होत हैं, जह जनता का सम्यन मी प्रायट होता है, व ससद के सदस्य होत हैं तथा उसी के प्रति उत्तरदायो होते हैं और ससद के प्रसाद-प्यत जपन पद पर स्तै है। मित्रमण्डलीय एक सामृद्धिक उत्तरप्याधिक का सिद्धात बिटिस ससदीय ध्यवस्था का

23 Max Beloff op est p 93

²¹ विभिन्त राष्ट्रपतिया द्वारा योग्य व्यक्तिया स समय-समय पर परामश किय पय हैं। इसम से कुछ जसे कनल हाउत एव टेरी होपिन स ने नाम विशेष प्रसिद्ध है एव उनका प्रमाय तत्कालीन घटनाओं पर पडा है। राष्ट्रपतिया द्वारा इस तस्ह आय व्यक्तियो स परामश करने का कारण मि प्रमण्डल स सदस्यों की सकीणता तथा उनम व राष्ट्रपति म असहयोग है।

²² Max Beloff The American Federal Government 1959, p 93

जाधार है। ब्रिटिश प्रधानम त्री सहयागियों की टीम का नंता होता ह। वह समकक्षी में प्रथम है। इसके विपरीत, अमरिकी मि नमण्डल के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। वे उसके परामश्चदाता होते हैं। राष्ट्रपति के वे जवीतस्य कमचारी है। उनके परामस एव विचारा को मानना या न मानना राष्ट्रपति पर निभर करता है। यह आवश्यक नहीं है कि वे सब एक ही राजनीतिक विचारधारा के सदस्य हो। अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्ति एव व्यक्तित्व में उनकी सम्पूण प्रतिमा जाच्छादित रहती है। मि त मण्डल के निणय राष्ट्रपति के लिए परामश मान है। अमेरिकी व्यवस्था म मिन-मण्डलीय सामृहिक उत्तरदायित्व का पूज अभाव है। सचिववण काँग्रेस के सदस्य नहीं होते । मात्री पद अमेरिकी राजनीतिक जीवन स अस्थायी अवकाश माना जाता है। उनकी तुलना में सौनेटर की स्थिति अधिक प्रमावशाली एवं हड होती है। बहुत से राष्ट्रपति अपने मित्रया से परामश करने की अपेक्षा सीनेटरी से परामश करना अधिक लामप्रद समभते थे। अमेरिकी मात्रीगण अपने पद स त्यागपत्र देकर अपनी स्थिति को वढा नहीं सकते, अपित् त्यागपन के साथ उनके राजनीतिक जीवन का अत हो जाता है। अमेरिकी मित्रमण्डल के सदस्य दिटिश मित्रयों की माति काग्रेस के नेता नहीं होते और न बिटिस मित्रमण्डल की भाति वह नीति का निर्माण ही करते है। राष्ट्रपति मित्रया का स्वामी है और उन सब म सर्वोच्च है। अमे-रिका में ब्रिटेन की बाति मित्रमण्डल को ज्ञासन की असफलता के लिए दोपी नहीं ठहराया जाता अपित राष्ट्रपति ही प्रशासनिक असफलता के लिए उत्तरदायी होता है। ब्रिटिश मित्रमा की तुलना म अमिरकी म भी का स्थान निस्स देह नीचा है। राष्ट्रपति सम्पण देश का प्रतीक है। अपने कायकाल म वह व य किसी प्रतिस्पर्धी अस्तित्व की स्वीकार नहीं करता है। उसके स्वर की तुलना में उसके म जी की आवाज मुनमुनाहट मान होती है जिसे सना भी जा सकता है और नहीं भी।

मिनमण्डल की हिषति का स्पष्ट करने के लिए राष्ट्रपति टापट (Taft) का निम्न कथन महत्वपूण है "मिनिसण्डल राष्ट्रपति की कृति है। यह एक अविधिक एव असवधानिक निकाय है। यह परम्परा पर आधारित है। यदि राष्ट्रपति इसे समाप्त करना चाहे तो कर सत्वता है। 1222 लेकिन 25वे सवधानिक सरोधन (1967 ई) के पारित होने के कारण मिनिसण्डल को सवैधानिक आधार प्राप्त हो गया है व्योक्ति इस साविधानिक सेवधान द्वारा मिनिसण्डल को कायपानिका विमाना के प्रमुख अधिकारियों के निकाय की मन्ना दी गयी है। 5

^{24 &#}x27;Cabinet is a mere creation of the President's will, it ii an extra statutory and extra constitutional body. It exists only by custom. If the President desired to dispense with it, he could do so'—Taft, W. H. Our Chief Magnitude and this Powers p. 30.

^{25 25}वे सशोधन द्वारा यह व्यवस्था भी की गयी है कि राष्ट्रपति की मृत्यु या मानसिक

अमेरिको राष्ट्रपति एव ब्रिटिश राजा

ब्रिटिश राजा नाममात्र की कायपालिका है। वह देश का सवधानिक अध्यक्ष होता है। वह वसानुसत आधार पर नियुक्त होता है। सवधानिक अध्यक्ष होने के कारण देश के प्रशासन में उसका कोई हाथ नहीं होता। सम्पूण कामपालिका प्रतिक्र प्रधानम त्री महिल मिं तमण्डल में निहित होती है और वह ही वास्तविक कायपालिका है। अमेरिकी राष्ट्रपति चिटिंग राजा के विषरीत वास्तविक एव प्रमुख कायपालिका है तथा राय्य मा निर्वाचित अध्यक्ष है।

सिखान्त म विटिश सम्राट अमेरिकी राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशामी है लेकिन व्यवहार में अमेरिको राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं अधिकार ब्रिटिश शाउन से कही अधिक हैं। काउन ससद के अधिवेशन का बाहुत, स्पणित एवं भग करता है । परन्तु अमेरिकी राष्ट्रपति की ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। विधि-निर्माण में अमेरिकी राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से योग देते की स्थिति में ही नहीं है। त्रिदिश त्राउन के मन्त्री विधि-निर्माण से महत्वपूर्ण भूमिका निराते हैं। ब्रिटिश त्राउन का सिद्धान्तत पूर्ण निर्पेधाधिकार प्राप्त है लेकिन आउन ने व्यवहार में कभी इस शक्ति का प्रयोग मही किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति को प्राप्त निवेशाधिकार आशिक (Suspensive Veto) है। काषपालिका एव प्रशासनिक क्षेत्र में नि विदिश काउन की शक्तिया सिद्धान्तत राष्ट्रपति सं अधिक हैं। त्राउन द्वारा की नयी निपुक्तियों की पुष्टि किसी जाय सस्या के द्वारा नहीं की जाती है लेक्नि काउन के नाम पर सभी नियुक्तियाँ प्रधानम भी के द्वारा की जाती हैं। इसके निपरीत, अमरिकी राष्ट्रपति की नियुक्तियो एव सी घंधों के सादस सं सीनेट के 2/3 बहुयत के समयन पर निमर रहना पडता है। बिटिश राजा नाममात्र का अध्यक्ष है, स्विषम सूच है। समस्त क्तिया मित्रमण्डल एव ब्रिटिश ससद को त्रमध हस्तान्तरित हो गयी हैं। सत ब्रिटिश काउन के नाम पर तो केवल शासन चलता है। सित्रमण्डल कायपालिका है एव प्रधानम त्री काश्रपातिका अध्यक्ष । लास्की के इस कथन थे पर्याप्त सत्य है कि "ब्रिटिश क्राउन अमरिकी राष्ट्रपति से अधिक प्रमावशाली भी है और कम मी।" यही सत्य इन शब्दो द्वारा व्यक्त होता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति शासन करता है जबकि बिटिश फ्राउन राज्य करता है।

अमेरिको राष्ट्रपति एव निटिश प्रधानमन्त्री¹⁴ विटिस नाउन के साथ बमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना करने की अपक्षा उसकी

अस्वस्थता के कारण उप राष्ट्रपति के राष्ट्रपति वनने पर वह किसी अय व्यक्ति को उप राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। पूत्र व्यवस्था के अन्तमन उप राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर सामामी चुनाव तक रिक्त ही रहता था।

²⁶ देखिए अध्याप 18

तुलना ब्रिटिश प्रधानम त्री से करना वाख्तीय है नयांकि प्रधानम त्री मित्रमण्डल सहित देश की वास्तविक कायणां लिका है। एक अब से यदि राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश प्रधानम त्री से भेष्ठ है, तो दूसरे क्यों मे हेय है। उसकी स्थिति इस अप म अंध्य है कि अमेरिकी राष्ट्रपति सच्चे कर्यों मे मित्रमण्डल का स्वामी है। इसके विष रीत, ब्रिटिश प्रधानम नी केवल समकतों मे प्रथम है। उसे अपने मित्रमण्डल को साथ लेकर चलना पडता है। ब्रिटिश प्रधानम त्री अमेरिकी राष्ट्रपति की माति अपने मित्रमण्डल को साथ लेकर चलना पडता है। ब्रिटिश प्रधानम त्री अमेरिकी राष्ट्रपति की माति अपने मित्रमण्डल की हर सदम म उपक्षा नहीं कर सकता। उसे अपने मित्रमण्डल के मत को स्वीकार करना पडता है। अत मित्रमण्डल प्रधानम की के ऊपर एक नियत्रण है। अमेरिकी राष्ट्रपति की स्थित इसके सवया मित्र है। उसके मित्रमण्डल के सदस्य क्षेत्रस्य कमचारी हैं। व उसके हारा मनीनीत हैं। उनके परामश को न मानने के लिए वह वृण स्वतान है।

उपरोक्त अतर के अतिरिक्त दोनो म निम्निखित मुख्य असमानताएँ हैं

(1) प्रभागमात्री मान्यस्थल का तेता होता है। वह लोकसभा का सदस्य होता है एव ब्रिटिश ससद के प्रति उत्तरदायों होता है। वह हमेवा हो अपनी जेव में त्यागपत्र सियं फिरता है। उसका काय काल निश्चित नही है। वह स्प्रत के विश्वास पयन्त पराख्य रहता है, स्पष्ट है कि इगलैण्ड में शक्ति पृथक्करण के मिद्धान्त को मान्यता प्राप्त नहीं है। इसके विपरीत, अमिरकी सविधान शक्ति पृथकरण पर गाया-रित है। राष्ट्रपति काग्नेस का सदस्य नहीं है और न उसके प्रति उत्तरदायों ही है। उसके मंत्री उसके सेवक हैं। उसका कायकास निश्चित है। यह चार वय के लिए नियंचित होता है। काग्नेस राष्ट्रपति को केवल महास्वियोग स्वाक्तर ही उसके पद स हटा सकती हं।

(2) विधि निर्माण के क्षेत्र म अमेरिकी राष्ट्रपति की श्राक्तियाँ अत्यधिक सीमित
हैं । त्रिटिश प्रधानमानी का इसके विषरीत विधि निर्माण में महस्वपूण हाथ होता हैं ।
देश का वार्षिक आय-व्यव पन—बजट—प्रधानमानी की सहस्रति स विक्तमानी श्रारा
तैयार किया जाता है एव ससद म उसे पारित कराने म मित्रमण्डल सहित प्रधानमानी महत्वपूर्ण पात है एव ससद म उसे विषरीत अमेरिकी राष्ट्रपति को बजट की
स्वीकृति के लिए सीनेट म अपने दल ने नताआ एव सीनेट के सदस्यों के सहयोग पर
निमर रहना पडता है ।

(3) ब्रिटिस प्रधानम त्री बहुमत दल का नेता होन के कारण ब्रिटिस ससद का नेता होता है। सबद के विद्रोह करने पर ब्रिटिस प्रधानम त्री उसके मन करने की मांग कर सरता है जिस नाजन अनिवायत स्थोकार कर सेता है। इमके विपरीत, अमेरिकी राप्ट्रपित कप्रिस का समक्स है। उसका प्रतिद्वन्ती है। बद उसने पन करने की पिक्त नहीं रखता, दोना सदना म मतनेद नो स्थिति म बह कप्रिस के अध्ययन ग्यन स्थागत कर सबता है। सकट कांग म विटिस प्रधानम त्री की सिक्ता म यदि 674 | बाधुनिक शासनता न

हा जाती है। वे उसकी शक्तिया न होकर मित्रमण्डल की शक्तियाँ होती हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति सकट-काल में कम वढ तानाशाह वन जाता है। ब्रिटिश प्रधान मन्त्रों को तुलना म सकट कान म उसकी शक्तियाँ बहुन वढ जाती हैं।

(4) अभेन्ति राष्ट्रपति देश की सेनाओ का प्रमुख सेनापिन है। यह शक्ति निटेन में त्राउन में निहित हैं। राष्ट्रपति को त्यमादान की शक्ति प्राप्त है। इंगलैण्ड में सिद्धान्त में यह प्रधानयात्री को प्राप्त न होकर काउन को प्राप्त है। संकिन व्यवहार म इन शक्तियों का प्रयोग मिनिमण्डल करता है।

(5) राष्ट्रपति राज्य एव शासन दोनों का प्रधान है, प्रधानमात्री केवल शासन का अध्यक्ष है।

लास्को ने दोनों को स्थितिया पर निम्न टिप्पणी को हैं "अमेरिको राष्ट्रपति में विटिश प्रधानम जी को विधायी शक्ति से ईप्या होनों चाहिए। विटिश प्रधानम जी निष्यत होता है। जब तक प्रधानम जी कोई भयकर भूत निर्देश न सक्ति उसके प्रस्ताव होता है। जब तक प्रधानम जी कोई भयकर भूत नहीं करता नव तक उसके प्रस्ताव सस्वीकृत नहीं होता। आजकल विधि प्रस्ताव सस्व द्वारा नहीं अपितु मतदाताओ हारा अस्वीकृत नहीं होता। आजकल विधि प्रस्ताव सस्व द्वारा नहीं अपितु मतदाताओ हारा अस्वीकृत नहीं होता। प्राप्त मतिय मामला में उस तथा उसके मिन्यमण्डल को पूर्वाण्य अस्वान प्राप्त होते हैं। विशेष परिस्थितिया के अतिरिक्त दलीम दबाव को उसे कोई आध्यका नहीं होती। प्राप्त मभी प्रस्तों के शिवारण म वह मौलिक भूभिका अदा करता है। प्रधानम नी रहते हुए वह दलीय य र का प्रमुख होता है। वह नॉमण समा का प्रमुख है। वह नामस्य समा को विधादित कर सकता है। है। वह नॉमण समा का मुख है। वह नामस्य समा को विधादित कर सकता है। इसके विवादित असेरिकी राष्ट्रपति काग्रेस का सभी स्वामी नहीं होता, न वह उसे नम ही विपरित अमेरिकी राष्ट्रपति काग्रेस का सभी स्वामी नहीं होता, न वह उसे नम ही कर सनता। काग्रेस के दोनों सदन राष्ट्रपति के निर्देश म कार्य नहीं करते। काग्रेस का सम्रेस का विधादित निर्माण है।

लास्की का यह मी मत था कि विटिश प्रधानय नी की स्थिति अमेरिसी
राष्ट्रपति जसी है। लेकिन यह मत माच नही है। प्रधानय नी चित्रल को भी वे
शक्तिया प्राप्त नही थी जिनका उपयोग राष्ट्रपति क्लवेस्ट ने किया था। यशि
प्रधानम त्री विचल को मिनिमण्डल ससद एवं राष्ट्र का पूण समयन प्राप्त था परालु
वह राष्ट्रपति फ्रेकिनिन डी क्लवेस्ट की मीति मिनिमण्डल नी उपेशा करके काथ नही
कर सनता था।

सपट है कि कुछ क्षेत्रा म जसे विधि निमाण एव वित्त व्यवस्था म ब्रिटिश प्रधानमंत्री बसेरिकी राष्ट्रपति संबंधिक शक्तिशाली है। लेकिन प्रशासनिक एव नगयगिकका सम्बन्धी भामला म राष्ट्रपति की स्थिति श्रेष्ठ है। प्रधानमंत्री एव राष्ट्रपति का पद बहुत कुछ उन व्यक्तिया के व्यक्तित्व पर निमर करता है जो उसे धारण करते है।

²⁷ Lasks American Presidency 1943 p 118

स्विस सघीय कार्यपालिका [SWISS FEDERAL EXECUTIVE]

प्रेसोडेच्ट लायेल ने स्विस संघीय कायपासिका—संघीय परिषद (Federal Council) को राष्ट्रीय झासन को सुरय पुरी (Main Spring) एवं सं तुलन चन की सभा दी है। स्विस सामूहिक कायपालिका, आर जी घोष के शब्दों में, आधुनिक लोकत न की एक सहत्वपूर्ण राजनीतिक सस्या है।

स्विद्जरलैण्ड की सथीय कायपालिका म ससदीय एव अध्यक्षारमक काय पालिकाओ की विशेषताओं का समयव पाया जाता है। इसे हम इगर्नण्ड की सपदीय प्रणाली एव समुक्त राज्य अमेरिका की अध्यक्षारमक प्रणाली के मध्य की व्यवस्था कह सकते हैं। साँड बाइस न इसकी विशेषता को व्यवस्था करते हुए कहा है कि 'क्सी मी अप स्थान विशेषता को व्यवस्था के तथा स्थान के स्थान के स्थान के 'क्सी मी अप स्थान के स्थान क

l स्विस सर्विधान म इसे Bundesrat की मना टी निर्मा है।

² The Federal Council may almost be regarded as the mandal scertainly the balance wheel of the National Government, 1926, p 316

न दलीय नीति निर्धारित वरती है, पर तु फिर मी पूणरूपेण दलीय रम स मुक्त नहीं होती है। 19

स्विस सभीय कायपानिका (फडरल नाउन्सल) सात सदस्या की एक समिति है जो चार वप र लिए सभीय समा (Federal Assembly) द्वारा चुनी जाती है। यदि नेदानल काउनल (सभीय व्यवस्थापिका का निम्न सदन) अपना चार वर्षाय अविध के पूर्व भग हो जाती है ना फेडरल काउसल का कायकाल भी उसी के साय समाप्त हो जाता है। लेकिन सामाय्यत एसा होता नहीं है।

संधीय पायद प्राम जितनी बार चुना जाना चाहता है, पुन निर्वाधित कर लिया जाता है। यह एक परम्यरा धी है। फलसक्टण कुछ सबस्या का कायकाल 20 स 32 वर्षों तक रहा है। इस्ता एक कारण यह भी है कि सधीय पायद बलीय हिट काण से कार्य निर्वाक्त करें। इस्ता एक कारण सक्या को नियुक्त नहीं किया जाता अधितु प्रधासकोय यांचाता, भागियक उन्हण्टता, पेटर स्वमान, प्रतिमा, काय-मुखलता आदि मुणो के वारण ज हे निर्वाधित किया जाता है। सभी सदस्यों की समान प्रक्तिय एवं अधिकार होते है। परिसम (Confederation) के अध्यक्ष को उनके निर्वाचन म कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। व किया ज विशेष दल के सदस्य नहीं होते, अपितु फेडरल अधेक्तीर (सधीय समा) डारा जनक चुनाव समा प्रमुख दल्ता म के किया जाता है। जनम मतमेद स्वामाविक होते है। सधीय समा में वे एक दूसरे का विराध करते हैं। एक सदस्य के डारा प्रस्तुत विधि प्रस्ताव की आसोवना दूसरे का विराध करते हैं। एक सदस्य के डारा प्रस्तुत विधि प्रस्ताव की आसोवना दूसरे का विराध करते हैं। एक सदस्य के डारा प्रस्तुत विधि प्रस्ताव की आसोवना दूसरे

³ Bryce Modern Democracies, Vol I, 1929, pp 393 94

सदस्यो द्वारा की जाती है। जत वे ब्रिटिश मिनमण्डल के सदस्यो की माति सामू-हिक रूप से काय नही करते है। व इयलेण्ड की माति प्रस्तावित विषेयक के अस्वी कृत होन पर अपने पद से त्यागपन नहीं देते वरन् अपने पद पर बने रहते है, न सभी सदस्यो द्वारा सामूहिक उत्तरसायित्व के खिद्धात के आधार पर एक साथ त्यागपन दिये जाते हैं। 1934 ई म हेवरसीन (Hacberlin) ने सावजनिक व्यवस्था सम्ब धी अपने विषेयक के जनमत सग्रह में अस्वीकृत होने पर परिषद की सदस्यता स त्याग पन वे दिया था।

फेडरल काउन्सल (सघीय परिषद) की शक्तियाँ

कायपालक काय—फेडरल काउ सल देश म शाति एव व्यवस्या की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। संधीय समा द्वारा पारित विधिया को यह किया वित करती है। विदेश नीति का निर्धारण एव किया वयन भी उसका दायित्व है। देश की सुरक्षा की व्यवस्था एव उसके लिए सेना की स्थापना तथा निय नण, कण्टनों के साथ पर-स्पर अच्छे सम्ब भ स्वान, बजट निर्माण एव संधीय समा द्वारा उसकी स्वीष्ठित परि पद के अयं कायपालक दायित्व हैं।

सधीय परिषद द्वारा वैदेशिक एव आन्तरिक मामलो सम्बधी एक प्रतिवेदन सथीय समा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। कंप्टनो द्वारा परस्पर एव विदेशा से की गयी सिधियों की परिषद जान करती है। यदि कोई कंप्टन सब शासन के साथ सहयाग नहीं करता है तो सधीय परिषद को इस सम्बध्य से आवदयक कायवाही करने का अधिकार है। कष्टनों के सिवेशाना पर भी सधीय परिषद निगरानी रखती है। अर्थात सधीय परिषद का यह दायित्व है कि बह देखे कि कष्टना के सिवधान स्वरूप में लोक तन्त्रीय एवं गणत त्रीय है तथा उनके सिवधानों म सधीय विद्यान विरोधी कोई व्यवस्था नहीं है।

सभी सपीय नियुक्तिया, केवल कुछ को छोड़कर, सपीय परिपद द्वारा ही की जाती हैं। सपीय प्रशासनिक अधिकारियों के आवरण का निरीक्षण करना भी परिपद का काम है। विशेष परिविद्यातियों में अर्थात सधीय सम्रा के सन्तवसान काल में या सकट काल में, सधीय परिपद को सेना के प्रयोग का गी अधिकार है। लेकिन परि-पद की सधीय समा का शीझातिशीझ अधिवंशन आहृत करके ऐसे मामलों को उसके समक्ष विचार हें पु प्रस्तुत कर देंगा चाहिए।

सधीय सविधान का पालन एवं रक्षा तथा संबीय यायालयों के तिणयों एवं कण्टना के विधादों सम्बंधी समकौतों एवं पच फैसलों को त्रियाचित करना परियद का ही दायित्व हैं।

े विधायी काय--विधि निर्माण काय म भी सधीय परिषद के सदस्य महत्वपूण भूमिका निमाते हैं । सधीय समा के समक्ष 95% विधि प्रस्ताव परिषद द्वारा ही उप हिंथत किये जाते हैं और परिपद के सदस्य उनको पारित कराने म महत्वपूण योग दते हैं। सामा प निषम यह है कि परिपद विधि-प्रस्ताव के प्रारूप की स देश या प्रतिवदन के रूप म प्रस्तुत करती है। अत सभीय परिपद द्वारा विधियों प्रस्तावित की जाती हैं। मामा यत सपीय समा इन्हें नेवल स्वराधित करती है। सधीय समा द्वारा निकी प्रस्ताव या मामले में परामद मौगन पर सधीय परिपद सम्बिप्त विषय पर परामदा मी देती है। अध्यादश जारी करने एव प्रदक्त विधान (delegated legislation) के अत्वत्त विधि कमाने का नीध तरा मी परिपद को प्राप्त है।

न्यायिक काय--विभिन्न प्रशासनिक विभागा एवं सयीय रनवं प्रशासन के निणयों के विरुद्ध भी से संपीय परिषद मं की जा सकता है। कैच्छों के कुछ निणयों के विरुद्ध भी संधीय परिषद मं पुनरावेदन किया जा सकता है—ज्येते धार्मिक आधार पर विद्यानया मं भेदभाव, निर्वाचन, कण्डना के मध्य पारस्परिक सचिया, व्यापार, सीमा शुरूव एटंट सम्बन्धी मामले। लेकिन इन विषया मं संधीय परिषद के निणय के विरुद्ध संधीय यायान्य तथा संधीय समा मं आवेदन किया जा सकता है। संधीय अधिकारियों के आचरण सम्बन्धी मामली का निणय संधीय परिषद यायान्य सन्धा के कुण मं करनी है।

वरिसंघ का अध्यक्ष

सधीय कायपानिका के सात सदस्या म से एक सदस्य को सपीय समा द्वारा एक वप के लिए स्विस परिसप (Sa.ss Confederation) का राष्ट्रपति (Presi dent) निर्वाचित विया जाता है। परिसप का एक उवाध्यक्ष मी हाता है। दौना पुन निर्वाचित किये जा सबत है परन्तु जगातार एक ही क्रम मे नहीं। परिपद के उपर-ध्यक्ष को अभिसमयानुसार लगामी वर्ष अध्यक्ष चुन लिया बाता है। राष्ट्रपति पद पर परिपद के सदस्यों की वरिष्ठता के क्रम से नियुक्ति की जाती है।

परिसम क राष्ट्रपति को स्थित सधीय परिपद क अप सदस्यों के समान ही होती है। बाइस के अनुसार उसे राष्ट्रपति मा परिपद के अध्यक्षक रूप में कोई विशेष शिक्तमाँ प्राप्त नहीं है। उसे केवल विवाद को स्थित में तिपरिपद मत प्राप्त है। वह अ म सदस्यों को मीति ही एक विमाग का अध्यक्ष होता है। परिपद क अप सदस्यों की निर्माण को परिपतित करते का उस कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वह परिपद के अधिवेशनों की अध्यक्षता करना है पत सम्मराहा तथा अय अवसरों पर औपवारिक रूप में देश के अध्यक्षता करना है पत सम्मराहा तथा अय अवसरों पर औपवारिक रूप में देश के अध्यक्षता करना है। विदेशी शासकों एवं राजदूतों का स्वागत सधीय परिपद सामूहिक रूप से करती है।

⁴ एम जीमुसेपी मोटा (M Giuseppe Motta) 5 बार, हरमूनर (Herr-Muller) 3 बार (1899, 1907 एव 1913) वमा डॉ फिलिप इटर 4 बार (1939, 1942, 1947 एव 1953) राष्ट्रपति चुने गये थे।

⁵ Bryce Modern Democracues, op cst , p 399

अत स्थिस परिसध का राष्ट्रपति केवल समकक्षा म प्रथम है। उसे 'महत्वहीन राप्ट्रपति' की सज्जा दी जाती है। उसकी स्थिति इगलण्ड के प्रधानम त्री एवं अमेरिकी राष्ट्रपति जैसी नहीं है। इगलैण्ड के प्रधानम नी की तरह वह संधीय परिषद का नेता नहीं है। वह ब्रिटिश प्रधानमानी की तरह सधीय परिषद के निर्माण, जीवन एवं मत्य के लिए के द्रीय स्थित नहीं रखता है। वह ब्रिटेन के राजा या भारतीय राष्ट्रपति की माति नाममान का हो कायपालिका-अध्यक्ष है । वह बिटिश सम्राट जसी शान शौकत नहीं रखता और न उसकी माति बशानुगत आघार पर नियुक्त ही किया जाता है। यद्यपि उसकी नियुक्ति संधीय सभा द्वारा की जाती है पर त भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन करने वाले निर्वाचक मण्डल की माति स्विस संघीय समा किसी निर्वाचक मण्डल का अग नहीं है। ब्रिटेन के राजा या मारतीय राष्ट्रपति की माति स्विस राष्ट्रपति किसी प्रशासिक विमान की अध्यक्षता नहीं करते है। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह वह कायपालिका का प्रमुख या मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भी नही है और न परिपद के सदस्य उसके सेवक ही होते है। परिषद के सभी सदस्यों का स्तर समान होता है एवं वह परिषद के अय सदस्यों की मांति ही एक सीमा तक उत्तरदायी होता है। सभी निणय सधीय परिपद द्वारा सामृहिक रूप में लिये जाते हु। परिपद के विभिन सदस्यों के मध्य वह एक कडी का काय करता है।

स्विस राष्ट्रपति का पद मते ही विक्त व प्रमाव का न हो पर लु सम्मान का अवस्य है । उसे सभीय परिषद के अपने सहयोगी सदस्यों की तुलना में प्राथमिकता एवं वरीपता प्राप्त है । प्राप्त प्रयोक स्विस राजनीतिज्ञ इस सर्वोच्च पद का प्राप्त करने की कामना करता है । प्राप्त प्रयोक स्विस राजनीतिज्ञ इस सर्वोच्च पद का प्राप्त करने की कामना करता है । काचा को के अनुसार, "वह कवल राष्ट्र की कायपालिका समिति का अध्यक्ष है अत उसे सदस्यों द्वारा किय जाने वाले कार्यों की सुवना रहती है तथा वह राज्य के नाममात्र के समारोह सम्ब भी कतव्या को पूज करता है।" स्विस सर्वीय परिषद यहुल (Plunal or Collegiative) कायपालिका है एवं अध्यक्ष के पद का कोई विद्याप महत्व नहीं है। अर हास ह्वपर ने तो यहां तक कहा है कि 'परिसप का कोई अध्यक्ष नहीं है और न कण्टमों में कोई पवनर ही है। सामूहिक प्रणाली द्वासन की परम्परागत प्रणाली है एवं मार्थ स्वटन्तरिक्ष के ही इसका प्रयोग होता है।"

स्विस सघीय परिषद एव सघीय सभा (अर्थात् व्यवस्थापिका)

सपीय परिषद को व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। वेकिन विधिक हिन्द से स्थित कायपालिका सपीय सभा से स्वतः प एवं उसके समनस नहीं है। परिषद सपीय

⁶ Lowell Greater European Governments, 1926, p 319

⁷ The confederation has no President, the cantons have no Governors The Collegial system is the traditional form of government and the only one use in Switzerland "—Hans Huber How Suit_crland is Governed, 1946, p. 5

सभा की सेवक है। उसकी स्थिति एक अधीनस्य जैसी है। इसका कारण यह है कि न्विस सर्विमान शक्ति पृथनकरण के सिद्धा त पर आधारित नहीं है। संपीय व्यवस्था-पिका द्वारा परिषद के मान सदस्यो एव अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचित किया जाता है। संघीय समा की स्थिति प्रमुख एवं प्रधान है। नीति निर्धारण में उसका स्यान प्रमुख है। सविधान की बारा 71 के अनुसार परिसध की सर्वोच्च सत्ता व्यवस्थापिका म निहित है। सधीय परिषद की शक्तिया केवल निरीक्षणात्मक हैं। उसे प्रत्येच बदम पर समीय समा से आदश ग्रहण करने पहते हैं। यदि परिपद के विचार या मत में संघीय सभा असहमत होती है तो परिषद के सदस्या को ही भूकना पटता है। परिषट के द्वारा प्रति वध संघीय समा या व्यवस्थापिका के समक्ष प्रतिवदन प्रम्तुत किये जात है। सकट काल ये व्यवस्थापिका द्वारा संधीय परिपद की व्यापक चित्तया प्रदान की जानी हैं । इस प्रदत्त चित्तवा की उसके द्वारा नापस भी लिया जा है। समय-समय पर मधीय सभा प्रस्तावा एव बादर्शा के रूप मे परिपद को अपने दाधित्वों का सम्पादित करन के सम्बाध में आदश देती रहतों है। परिपद के सदस्य संघीय व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं हात परातु व संघीय सभा के अधिवेशना म भाग लेत है, प्रश्ना का उत्तर देते है एव आवश्यकतानुसार स्पप्टीकरण प्रस्तुत करते हैं। परिपद द्वारा संघीय सभा के आदेशों का राष्ट्र के आदेश के रूप म उसी प्रकार क्यिया वित किया जाता है जिस प्रकार एक सबक अपने स्वामी के आदेशों की निया वित करता है। स्ट्राम के अनुसार, मात्रीगण सदन ने नता नहीं होते अपितु सवक ही होते हैं। लाबेल ने इमी विचार की दूसरे शब्दों म प्रस्तुत करते हुए कहा है कि 'स्विट-जरलण्ड क सावजनिक जीवन ना यह एक मा य सिद्धा त है कि पापदा (councillors) द्वारा एक बकील अथवा शिल्पकार की मौति परायश दिया जाता है। यदि उनके परामश को स्वीकार नही किया जाता है तो वे पदत्याग के लिए बाध्य नहीं हु। "

विधिक हिन्द से परिवस सपीय सभा के अधीन है। तेकिन व्यवहार म ऐसा
नहीं है। परिवद में अनुमदी राजनीतिज्ञ होत हैं अत ने व्यवस्थापिका का नेतत्व करते
हैं। साँछ ब्राह्म का मत है कि 'ब्रधानिक होट्ट से परिवद व्यवस्थापिका को समक है
परन्तु व्यवहार म वह इमलेक के मीं नमण्डल की माँति नेकिन फास के मि नमण्डल
से अधिक शांकि का प्रमीण करती है।' 10

8 "The Ministers are not the leaders of the Houses but are their servants' -Strong of at p 268

10 Bryce Modern Democracies, Vol I 1929, p 397

^{9 &#}x27;It is a general maxim of public life in Switzerland that on official affairs, he gives his advice, but like a lawyer or an architect, he does not feel obliged to throw up his position because his advice is not followed —Lowell Greater European Governments 1926 pp 319 20



इसे अध्यक्षात्मक प्रणाली भी नहीं कह सकते। अध्यक्षात्मक व्यवस्या म शासन में शक्ति पृथवनरण, व्यवस्थापिका के प्रति कायपालिका के उत्तरवायित्व का अमाव एव कायपालिका तथा व्यवस्थापिका का कायकाल निश्चित होता है। राज्य का अध्यक्ष ही कायपालिका का प्रमुख होता है। स्विस संघीय परिषद अमेरिकी राष्ट्रपति की माति शासन का एक पृथक अग नहीं है। स्विस परिपद बहुत कायणालिका है। अमेरिका म एकल कायपालिका है। स्विस परिपद के अध्यक्ष की स्विति अमेरिकी राष्ट्रपति की वुलना म नगण्य है। अमेरिकी राष्ट्रपति को कावेस द्वारा नहीं चुना जाता। इसके विष रीत, स्विस परिपद के सदस्यगण व्यवस्यापिका द्वारा चुने जाते हैं। स्विस परिपद के सदस्यो की माति अमेरिकी राष्ट्रपति के म त्रीगण व्यवस्थापिका क अधिवेशना म माग नही लेते हैं। वे राष्ट्रपति क डारा नियुक्त किय जाते है और उसी के प्रति उत्तरदायी होते है। स्विस तथीय परिपद के सदस्या की मांति जनका चयन व्यवस्थापिका द्वारा नहीं होता। अमेरिका व सचिव राष्ट्रपति के परामश्चदाता है—जनके परामश्च को स्वीकार या अस्वीकार करता राष्ट्रवित की इच्छा पर निमर करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति व्यवस्यापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, उसका कायकाल निविचत होता है। परिपद का कायकाल भी निश्चित है। उसके सदस्य मते ही व्यवस्थापिका द्वारा चुने जाते हो लेकिन व्यवस्थापिका उहे जनके पदा स पृथक नहीं कर सकती है। बत स्वित स्पीय के मध्य पनिष्ठ सम्ब म—तथा अध्यक्षारमक प्रणाली की विशेषता—स्थायी कायकास— को संयुक्त करना सम्मव हो सका है। स्विस परिषद अमेरिकी राष्ट्रपति की मौति स्वत न सत्ता नहीं रखती है, उसके कार्यों पर सधीय व्यवस्थापिका का निय प्रथ होता है।

अंत स्विस सघीय परिपद स्वह्म में न तो ससदीय है और न ही अध्यक्षात्मक। यह ससदीय एव अध्यक्षात्मक प्रणातिया का मिश्रण या मध्यमाग है। इसम रोनो के गुणा का सम वय एव जनके दोपा के प्रतिकार का सफल प्रयत्न किया गया है।

लोक-सेवा (THE CIVIL SERVICE)

लोक सेवा हो आधुनिक राज्या की स्थायी कायपालिका है। मिनमण्डल एव राष्ट्रपति जनता द्वारा एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित किये जाते हैं पर तु लोक-सेवा के सदस्यों का कायकाल निश्चित होता है। मिन्नमण्डलीय व्यवस्था से मिन-मण्डल के सदस्य अपने पदा पर ससद के प्रसाद चरा हो रहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का कायकाल निश्चित है लेकिन उसके अधीन काय करने वालो सासकीय कमचारिया की स्थिति इससे मिन्न होती है। उनका पद स्थायी होता है। सासन की नीतियों मिनमण्डल एव राष्ट्रपति द्वारा निर्धास्ति की जाती हैं परन्तु उनके क्रियाचयन का दायित्व लोक सेवा के सदस्या के विद्याल समूह पर हो होता है। सामाय जनता का लोक सेवा के साथ ही सम्याय एव सम्पक्त होता है। अत लोक सेवा शासन त'न का महत्वपूण एव प्रभावशाली अग है। मिनमण्डल के सदस्य विभाग के राज्योतिक अध्यक्ष होते हैं। उनके अधीन लोक-सेवा के सदस्य उस विभाग के स्थायों कमचारी हात हैं। उन्हें स्थायी कायपालिका (Permanent Executive) की भी सना दो जाती हैं।

हरमन फाइनर के अनुसार, "लाक सेवा परोवर अधिकारिया का एक समुदाय है जो स्थायी बेदनमोगी एव कुशल (२०१) होते हैं ।" 1931 ई के लोक-सेवा सम्बाधी साही आयोग ने जिटिस लोक-सेवा की परिमाणा निम्म सम्बाध में इस प्रकार से हैं "नाउन के राजनीतिक एव "याधिक पदाधिकारियों के अतिरिक्त असनिक पदा पर नियुक्त माउन के सेवक लोक संया के अन्तमत आत हैं और उन्ह बेतन सीधे ससद द्वारा स्त्रीकृत धन म ल प्राप्त होता है।" इसका अथ यह है कि सनिक एव याधिक

¹ The Civil Service is a professional body of officials, permanent, paid and skilled "-Finer op cit, p 709

² The British Civil Service has been defined as those servants of the Crown, other than holders of political and judicial offices.

अधिकारी लोन सेना क अतगत नहीं वात हैं। संयुक्त राज्य अमरिना एवं प्रेट निटन सहस्र देसा म वैत्रानिक एव अय पेसा स सम्मी पत सेवाओं को तोर-सवा म पपक पाना गया है। आधिक त्रियाएँ भी अत्यधिक तकनीकी होती जा रही हैं अत एक युभाव यह भी है कि इन त्रियाओं क लिए प्रयक्त से आधिक सेवा का गठन किया जाना चाहिए । सक्षेप म, लोक सेवा का अथ गर-तकनी ही (non technical) हेबाएँ हूँ । लोक सेवा क लिए दूसरा प्रचलित शब्द 'ब्यूरोज़िसी' (Bureauctacy) है। यह फ़ॅच मापा का शब्द है। ब्यूरो (Burcau) का अथ मज या उत्तव है। अतं ब्यूरोक्रकी का अथ मज या उसक क शासन स है। हिंदी भाषा म ब्यूरोनसी क लिए हम नीकरसाही सन्द का प्रयोग करग । नोकरवाही का प्रयोग अच्छे अय म नही किया जाता, अपितु नौकर-साही का पणा की हिन्द स देखा जाता है। सामा यत जीकरशाही म निस्कुराता, अफतरताही एवं विलम्ब जत दोव निहित हैं। पूरोव म इस सब्द का प्रयोग सामा यत शासकीय वसवारिया के लिए किया जाता है। अधिकारियों म एक विशेष अकड तथा वर्गीय मावना होती है और व जनता से अधिक मनजोत नहीं बढात हैं। नियम का अक्षरक्ष पालन, निषय म बिलम्ब, नवीन प्रयोगा क प्रति अनास्या नीनरहााही की विहोदताए होती हैं। लास्की कं अनुसार, 'यह शासन की एक ऐसी पद्धित है जिसम अधिकारियों के हाथा म नियायण होता है जिससे सामाय नागरिक की स्वामता को हाति होती है । ¹¹⁶ नोकरसाही को यदि देशेवर कमवारी मान तिया वास तो वे सासन के लिए अपरिवास वन जात हैं। विसोबी न प्रशा के राज्य कमचारियों के लिए मोकरशाही (Bureaucracy) शब्द का प्रयोग किया है। लोक सेवा के काय

लोक सवा के विमिन प्रकार के नाय हैं। सासन की नीतियां को कियाचित करना जनका मदुद्ध काय है। नीति निर्माण म वरिष्ठ एव उच्च कमचारिया द्वारा पहुरोग भी किया जाता है। सचिव एव उप सचिवा द्वारा नीति के सम्बन्ध म मित्रयो भवार पार्ट के प्रमुख दिय जाते हैं। नीति के किया नयन के सम्बाध में अधीतस्य कमवारियो को निर्देश देने तथा निस त्रण और निरीक्षण (direction, control and supervi sion) के अधिकार होते हैं। प्रदत्त विधि निर्माण एव प्रशासकीय यायिक सम्बन्धी अव्धा क नामार हाव हा करते हैं। उदाहरण के सिर, विभागाच्या क रूप म उहं अपन अधीनस्य के लिए नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। आय कर आयुक्त

who are employed in a civil capacity and whose remuneration is paid wholly and directly of the money voted by the Parlia July 1961 p 1 Civil Service, BIS Pumphlet No R 4985, Tyagı, A R Public Administration 1972, p 352

⁴ Laski, quoted by Avasthi and Maheshwari in Public Admini-

द्वारा आय-कर अधिकारी के निषम के निकद्ध अपील सुनी जाती है। यह उसका न्यायिक कतन्य है। व जनता से सम्पक स्थापित करते हैं तथा धासन की नीतियों के उद्देश की स्पप्ट नरत हु एव सम्बच्धित आर्तिया वा निवारण वरत हैं। धासकीय नीति के श्रिया-वयन म जन सहयोग प्राप्त करता उनका महत्वपूर्ण काय होता है। सावजनिक सवा, निकत धासकीय काय, करा वा एकचोकरण, धासन-काय, वैवानिक धोध आदि कार्यों पर निरोक्षण रखना लाक तथा वा हो दायित है।

सारत म जिला अधिनारी (District Magistrate) की स्थिति लोक-सेवक (Civil Servant) की तुलना म मिन्न है। वह करा को एकत्र करने वाला राजस्व अधिकारी मां हे तथा जिला का प्रमुख दण्डाधिकारी (Magistrate) मी। स्वत नता के पूब तक वह जिले की सरकार था। वह राजस्य एव कीजदारी मामला म अपने क्षेत्र म सर्वोक्च अधिकारी होता था। अब 'याधिक अधिकारी उसने की नीधिकार मे नहीं हैं। वह जिले म नियोजन में लिए प्रधान रूप से उत्तरदायी होता है।

लोक सेवा को मुख्य विशेषताएं

ई एन म्लेडन के अनुसार लोक सेवा के सदस्यों का निव्यक्षतापूर्वक चयन किया जाना वाहिए तथा राजनीतिक निष्पक्षता, प्रसासकीय पट्टता एव सामाजिक सेवा माव से उन्हें परिपूर्ण होना चाहिए। है लोक सेवा की मुस्य विशेषताएँ निम्नवत हैं

- (1) सोक सेवा बृत्ति इयं मे---लोक सवा एक वित्त (पेशा) है एवं लोक सेवक (Public Servants) येतेवर कमचारी (professionals) होते हैं अर्थात् लोक सवा के सदस्य सरकारी श्रीकरी को जीवन ग्रापन के साधन के रूप म अपनात है। लेकिन इसका यह अय नहीं है कि लाक सेवा के विश्वित योणी के कमचारिया को एक ही अफार की योग्यता एव कुश्रालता की आवस्यन्ता होती है। अपितु विश्वित्त योग पर नियुक्त विश्वित्त लोक सेवको म विश्वित्त प्रकार की कुश्रालता एवं ग्रोग्यता की आवस्यन्ता होती है। अपितु विश्वित्त योग्यता एक श्रीचर नियुक्त विश्वित्त लोक सेवको म विश्वित्त प्रकार को कुश्रालता एवं ग्रोग्यता की आवश्यकता होती है। लोक सेवा एक ही प्रकार को युक्त नाम है जा राज्य की नीतियां को क्रियां वित्त करने के एक सामा ग्र उद्देश्य की प्राप्ति में सलग्त हैं। अत लोक सेवा के सदस्यों की मतीं, प्रशिक्षण एवं सेवा की शतीं के सम्बन्ध में उपित प्रशाली के विकास की आवश्यकता है।
- (2) अति आवश्यक—लोक सेवाएँ यति आवश्यक (urgent) होती हैं। प्रश्न यह है कि इन कार्यों को राज्य द्वारा मन्यादित करने की क्या आवश्यकता है?

⁵ Based on Finer op cut, pp 714 720

^{6 &}quot;Briefly summarized, the requirements of the Civil Services are that it shall be impartially selected administratively competent politically natural and imbued with the spirit of service to the community"—Gladden The Civil Service 1956, p 35

यारात्र म यह बाव एवं गावित्व राज्य व जिहार एवं मराज्ञ के हिए निज्ञान जावस्थव है। जम जहरात्र हिल्लामा एवं गावित्व निज्ञान जारायवन है। जम अहरात्र हिल्लामा वाहि जनकार वाहि वाहि स्वाहित की स्वाहित स्वाहित एवं स्वाहित स्वाहि

- (3) ध्यापक सगठन--- तार गया भाग र ध्यापक (a large scale) मगठा है भीर उन गर साथ का पुत्र सर्वाधिकार (r onopoly) है। गामकीय कथपारी इस प्रवार नाय करा है कि गया व्यक्तिया का आवश्यक मवार्ग उत्पारण है। सकें। पूर्वि राज्य ना भाग भागा पर स्वाधिकार साथ है भाग प्रवाद मुख्यावत हम सम्बद्ध सियाया भाग कर भग एक सिंबा उद्याद्य कथायों को स्वीति नहीं कर गर र स्वाध्यक्त मां
- (4) जाता क साथ समाव ध्यवहार—गंभी क गाय साह-गरा समान ध्यव हार करार ? (Equality of Tecatrical) । नोक-गराव का अपने आपरण म प्रा पिया होता पाहिल । उन्हें हिमा क गाय कार्द स्थियत या पंथापत नहीं करता पाहिल और तिथि का मुमा। व्या में बिता किया के निया के पिया ता करता पाहिल। उत्तर आपरण जाता (annon-mous) होता पाहिल। उत्तर पाहिल । उत्तर पाहिल । विश्व प्रमान कर्या मा उत्तर मुगा क प्रमान कर भागर गरिवाल से क्या क्या क्या क्या गाय गा वर्य में बामना किय किया शिक्य क्या साथ कर्या किया किया करता पाहिल पाह पाहिला क्या सुध पास सहमा को गायिया कर किया विश्व करता पाहिल पाह पाहिला क्या सुध पास सहमा हा अपना गहा।

राज्य-सम्पासे क्यार सम्पासी हो। है, व राजनीतिन या विपायक नही हो। । उन्हें भयत परामत ना। पाहिए एवं सासनीय नीति को त्रियाचित्र करना पाहिन । व व्यापानिया का मीति जागा संबंधित में सूर्य जनता न गृही न महते। व राज्य ने नियमा द्वारा निर्धारित सीमाओं के भावमत नाय नरत हैं। उन्हें एक हामा तथा विपाया न जानत क्षांव्यनीय मंदिनार प्राप्त होते हैं परन्तु जनन विरद्ध जनता ना सुन्य ही विपायी एवं नायिक सुरुगा प्राप्त होती है।

(5) जनता के श्रति बसरवायिय-सार-चपार व्यये नायों के लिए जनता के श्रीत उसरवायिय सार सार-चपार व्यवे नायों के लिए जनता के श्रीत उसरवायी होती हैं (Public Accountability)। सारन त्रीव देगों में एत तरीका ना विज्ञान हुआ है जिनक द्वारा क्ष्मणारिया को जनता के श्रीत निधिया के प्रति उसरवायी बनाया गया है। ये नोच ने बतन में तरती हुई महती की निधिया के प्रति उसरवायी बनाया गरी। है और उसके नायों ने लिए उस विष्कृत किया जा तरता है। एकत राज्य-क्षमणारी अव्यत्त चीन हा रहते हैं। ये सब इसके लिए प्रयत्नतीय रहते हैं। उसरवायी का प्रति प्रयत्नतीय रहते हैं। उसरवायी स्वर्थित वामका तरता है। इसते हम के स्वर्थित वामका तरता है। उसरवायिय के सम्बर्धित वामका तथा विधि का मुक्ततम अध्ययन कर सत्त हैं। उसरवायिय के

फलस्वरूप अपीनता एव परसोपान प्रवासी (herarchy) का विकास होता है। विरिष्ट अपिवारी अपने अपीनस्था के केवल उसी परामसको स्वीकार करते हैं जिसकी वह रक्षा कर सकते हैं। फलस्वरूप विभाग के युवक कमचारिया को नीति निर्माण में योग देने के बादित अवसर प्राप्त नहीं हो पाते और नासफीताशाही का दाय उत्पान हो जाता है।

- (6) पद सोपानीय समठन (Hierarchical Establishment)....राज्य की प्रष्टुति एव सुनिविचत नायक्षेत्र के फलस्वक्य पद सोपान पद्धति पर आधारित विभागीय सगठनों का विकास हुआ है। विभाग के विभाग स्पाद्याते को पद, कार्य एव वेतम की हिन्द से श्रीचया से वर्गोक्तत कर दिवा गया है। पद सोपान प्रणाली का मुख्य सिद्धात्व यह है कि प्रत्येक कमचारी अपने सं उच्च कमचारी के अधीन होता है एव आदेश के कारण एकता के सुख में आदद रहता है। निम्न अधिकारी अपन सं वरिष्ठ अधिकारी के प्रता ते सुख से आदद रहता है। निम्न अधिकारी अपन सं वरिष्ठ अधिकारी के प्रता ते हैं। विभागीय समठन सीनिक समठन की तरह होते हैं और सभी काय उचित कमानुसार (through proper channel) होते हैं।
- (7) जनता से सम्यक-लोक सवा के सदस्या का जनता से सीधा सम्पक होता है। इसक फलस्वरूप लोक सवा के प्रति चनता से अपेक्षाकृत अधिक घणा पायी जाती है। व्यवस्थापिका एव कायपालिका की गलत नीतियो एव विधिया के लिए सामा य जनता राज्य नमचारियों को ही दोषी ठहराती है। उन्ह शासन की नीतिया की जियान्त्रित करते समय औपचारिक एवं कठोर जाचरण करना पडता है। यदि वे विसी व्यक्ति का हित करना चाहते है या उसे लाम पहुँचाना चाहते हे तो उन्हें यह काय भी धीरे धीरे एव अनिबद्धापुवक ही करना पडता है। फलत शासकीय कमचारिया के प्रति जनता में विरोधी मावना व्याप्त हो जाती है। लोक सेवव को किसी भी प्रकार निदयों या नूर (ruthless) नहीं होना चाहिए" तथा उनका दृष्टिकीण परोप-कारी होता चाहिए। यह सामा य विश्वास है कि राज्य एक आदश मालिक (emp loyer) है । लोक सेवा में व्यक्तिगत प्रतिस्पद्धा के लिए काई स्थान नहीं होता है। अत जा एक बार शासकीय सेवा म मर्ती ही जाता है वह जीवन भर उसमे बना रहता है। महयोगी व वरिष्ठ अधिकारिया द्वारा परस्पर एक-इसरे ने निए कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं क्या जाता है। बनुवासनात्मक कायवाही बहुत कम ही जाती है एवं सरकारी सेवा में से बहुत कम व्यक्तियों को ही निकाला जाता है। अत इन सीमाओं के अधीन काम की उचित (workable) परिस्थितिया का निर्माण लोक-संवा के लिए महत्व का विषय वन गया है।

लोक-सेवा का इतिहास

प्राचीन मिस्र म लोक सवा के किसी न किसी रूप में प्रचलित होने ने प्रमाण

⁷ Finer op cut , # 719

मिलते हैं। प्राचीन मारत एव चीन म भी राज्य कमचारिया की नियुक्ति की प्रधा प्रचित्तत थी, लेकिन प्राचीन यूनान म लोक सेवना ना वन नहीं पाया जाता था। एथे स मे अधिकाश कमचारी जनता द्वारा निर्वाचित किये जाते थे और वहाँ गण तानीय रोम की तरह की कोई लोक सेवा नहीं थी। रोमन साधाज्य म अनक प्रकार के प्रशासकों की नियुक्ति की भयों और महत्वपूर्ण पदा पर नेवल कुलीनत त्रीम वम के व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता था। मध्यपुर्णीन यूरोप म परेवर राज्य-कम्-चारियों का उदय हुआ जिनम अधिकाश कमचारी मध्यम वग म मर्ती किये जाते थे।

हा ह्वाइट के अनुसार का स मे रिचनू (Richlieu), त्रिटेन मे हेनरी अप्टम एव महारानी ऐतिजावय प्रयम तथा प्रदा म इतेक्टर महान् (The Great Elector) वे प्रमुख शासक है जिल्लाने मध्ययुगीन सामन्ती व्यवस्था के मध्य से राज्य, पद, नागरिक-जीवन एव स्वायो पदाधिकारियो की धारणा का विकास किया था।

प्रशा की लोक सेवा (Prussian Civil Service)

लोक सवा का आधनिक युग में सवप्रथम विकास प्रशा म हुआ था । 1640 से 1786 ई तक प्रचा पर चार राजाओ का दासन रहा था। इनम से तीन राजा महान इलेक्टर फेन्टरिक विलियम एव फेडरिक महान योग्य एव विलक्षण प्रशासनिक क्षमता से युक्त थ । प्रशा म लोक सेवा की स्थापना एव विकास उपरोक्त शासकों का काय था। वितास वर्षीय युद्ध से जन, धन एव सस्थाओ की अत्यधिक हानि हुई थी तथा युद्ध के पश्चात राजस्य एवं सैनिक प्रणाती का पुनगठन एक समस्या थी। राज्य के क्षेत्रफल तथा जनसङ्या में वृद्धि के साथ राज्य कमचारियों की सख्या म भी वृद्धि हुई थी। आधिक विकास के लिए शीझ निषय की समता, ईमानदारी एव प्रशासनिक शक्ति सं युक्त राज्य-कमचारियों की आवश्यकता थीं। फलस्वरूप प्रशिक्षित लोक-सेवा का महत्व अनुभव किया जाने लगा और शक्तिशाली लोक सेवा ने प्रशा के एकीकरण म भी योग दिया । के द्वीय शासन स विमिन्न विभागों की स्थापना की गयी । प्रशा म स्यायी सेना थी जिसकी मर्ती सीचे के दीय शासन द्वारा की जाती थी। जिला मे मी राज्य द्वारा अधिकारियो की नियक्ति की गयी थी। जिला अधिकारियो (Kreisdirek tors) की नियुक्ति प्रारम्भ मे सनिक उद्दश्य से की गयी थी पर तु वीघ्र हो व जिलों में केंद्रीय शासन के सीचे प्रतिनिधि के रूप में काय करने लगे । अवकाश, काम के घण्टे, पद्धति, गोपनीयता एव अनुशासन बादि के सम्ब ध म नियम बनाय गय । जनता से सम्पक्त रखने बाले कमचारिया को विनम्रतापूर्वन आचरण के आदेश दिये गये। व्यापारिया को अपमानित करने पर प्रथम अपराध के लिए कर दण्ड एव बाद म

⁸ White The Civil Service in Modern States, 1930 p 11

⁹ Finer ob at p 727



ब्रिटिश लोक सेवा (The British Civil Service)

विदिश लोक सेवा को विश्व की सबयेष्ठ लोक संवा माना जाता है। फाइनर ने इसकी वडी प्रश्नसा की है। उसने अनुसार बिटिश लोक सवा सहश तकनीकी धमता एव मानवीय सेवा का सम वय अय सेवाओ म नहीं मिलता है। ' ग्राह्म वालास के अनुसार लोक सेवा का सम वय स्वयं सेवाओ म नहीं मिलता है। ' ग्राह्म वालास के अनुसार लोक सेवा का सप्वयं प्रथम विश्व के इगलण्ड का एक महान् राजनीतिक आविक्तार है। ' राज्य के मित्रयो, सचिवा एव परामवदातामां द्वारा जो कमवारी नियुक्त किये जाते थे व उनके द्वारा व्यक्तियत रूप से नियुक्त किये जाते थे। वे मित्रयो के व्यक्तिगत सवक हुआ करते थे और उनके द्वारा ही पदच्युत किये जाते थे। व्यक्तिगत सवक हुआ करते थे और उनके द्वारा ही पदच्युत किये जाते थे। व्यक्तिगत सवक हुआ करते थे वो विकास हुआ। महाराती विवहीरिया के मिहासनास्ट होने के 150 वर्षों पूत्र से राजनीतिको एव साकविष कमचारिया म भेद किया जाने लगा था। 1832 ई सक विदेन मं लोक सेवा मे 21 हजार व्यक्ति थे।

19वी सदी के उत्तराद्ध म सोक हेवा मे सुपार हुए थे, कलस्वरूप उस आधार भूत पढित का विकास हुआ जो बतमान ब्रिटिश लोक सेवा का आधार है। आधुनिक लोक सेवा के सत्वचा मे 1854 ई म नॉयकोट एव ट्रेबिलियन¹⁶ ने स्वायी लोक सेवा सगठन सम्बच्धी एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इही युआयो पर ब्रिटिश लोक सेवा आधारित है। इस आधोग की मुख्य सिफारियों इस प्रकार है—परीक्षा की उपित प्रणाली द्वारा योग्य व्यक्तियों का चयन, योग्यता के आधार पर पयोन्तित, समी कमचारियों को विक्रित विमाणों में पदी नित के बवसर देना तथा लिपिक वग की स्थापना जिससे सामाय रूप से उनकी सेवाएँ सभी विमाण का उपलब्ध हो सके। इन सुधारों को घीरे धीरे कुछ वर्षों म रियानित किया गया था।

1855 ई म लोक सेवा आयोग (Civil Service Commission) की स्थापना की गयी थी। इससे पूब प्रत्येक विभाग को अपने कमचारियों का चयन एवं नियुक्त करने की स्वत थता थी। सामा यद स्वीकृत पूनतम योग्यता सम्बंधी कोई मानदण्ड नहीं था, न कोई परीक्षा ही होती थी। काम तो चल रहा था परन्तु लोक सेवाओं में केवा ब्यापन थी। लोक सेवा आयोग के काय विभागाण्यक्षा द्वारा खोटे पदो के लिए मनोनीत नामों की समीक्षा करना तथा यह देवना या कि वे पद के सायित्व क अनुरूष आवस्यक यूनतम योग्यता रखते है या नहीं। विभान विभागों

¹⁴ Quoted by E Assrvatham Political Theory op cut, pp 384 85

¹⁶ Northcote Trevelyan Report on the Organisation of the Perma nent Civil Service, 1854

द्वारा जो पृषक पृषक परीक्षाएँ सो जाती थी उनके स्थान पर आयोग द्वारा एक परीक्षा सर्वातित की थी।

1870 ई का आदेश लोक सेवा के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके द्वारा विभागीय नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएँ अनिवाय कर दी गयी। 1874 ई मे प्लेफेयर आयोग (Playfair Commission) द्वारा कमचारियो के चयन, हस्ता तरण एव वर्गीकरण के सम्बाध म अधिक विस्तृत सुधारो के प्रस्तान रखे गये। लोक सेवां में तीन श्रेणिया बनायी गयी-प्रशासकीय या स्टाफ अधिकारी, उच्च तथा निस्त सम्मागीय कमचारी । रीडले आयोग (1886 90) (Ridley Commission) द्वारा प्रथक रूप से बूछ विमागों के संगठन आदि के सम्बाध में सिफारिशे प्रस्तुत की गयो। आयोग ने काय विभाजन तथा हर प्रकार के काय के लिए प्रथक व्यक्तियां की मतीं का भी सुकाव दिया । मक्डोनल वायोग, 1912-15 (MacDonnell Commis sion) ने देश की शिक्षा प्रणाली एवं लोक सेवा की परीक्षाओं म घनिष्ट समयप का सुभाव दिया । ग्लैडस्टोन समिति (Gladstone Committee, 1918) एव टोम-लिन आयोग, 1931 (Tomlin Commission) द्वारा भी महत्वपूण मुभाव दिये गर्य थे । टोमलिन आयोग न राज्य कमचारियो की चार प्रमुख श्रेणियो-प्रशासकीय, नाय-पालिका, लिपिक (clerical) एव सहायक लिपिक-के निर्माण का सुभाव दिया था। समस्त शासकीय पद स्त्री एव पुरुषों के लिए समान रूप से खोल देने का भी सुभाव दिया गया था। दितीय विश्व-यद के उपरा त राज्य-कमचारिया की सेवा सम्बंधी शती (service conditions) के सम्बाध म विचार-विमय हेत् प्रीस्टले आयोग (Priestley Commission, 1953 55) की स्थापना की गयी थी। आयोग ने काम के घण्टो की कम करते, एक सप्ताह मे पाच दिन करते. काय अवकाश भत्तो को कम करने एवं वेतन वृद्धि का सुभाव दिया।

पिटिश लोक सेवा म तीन प्रकार की श्रेणियाँ (classes) हैं

(1) सामा य सेवा श्रीणया (General Service Classes)—इसमे प्रशास-कीय, कायपालक, लिपिक एवं अय सब वेतनप्रागी कमचारी होते हैं।

(2) विशेषक श्रेणियाँ (Specialist Classes)—इसम वैज्ञानिक, तकनीकी

एव विशेष रोजगारों में सम्बिधत कमचारी शामिल होते है।

(3) विभागीय श्रेणिया (Departmental Classes)—इसना सम्बर्ध एक विभाग के कमचारिया से होता है, यथा—राबस्य मण्डल के कर निरीक्षण कार्यान्स्य (Tax Inspectorate)।

वैदेशिक सेवा (Foreign Service), समुद्र पार लोग सेवा (Oversea Civil Service) एव उत्तरी आयरलेण्ड की लोक सेवा उपरोक्त श्रीणया से पृषक है। 17

¹⁷ The British Civil Service op cat, pp 7 10

ब्रिटिश लोक सेवा पर कोषागार या ट्रेजरी विभाग का नियात्रण होता है। सपुक्त राज्य अमेरिका मे लोक सेवा (The U S Civil Service)

संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशासन में लुट प्रथा (Spoils System) प्रचलित थी। इसके अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन के पश्चात विभिन्न शासकीय पदो पर सैंकडो की सरयामे विजयीदल के व्यक्तियाको नियुक्त कर दिया जाता था। इस प्रथा के लिए प्रधान रूप में राष्ट्रपति एण्ड्रू जकसन (Andrew Jackson) उत्तरदायी थे, यदापि लघु रूप से यह क्ष्रया वार्शियटन, जैफरसन एव एडम्स के समय से ही प्रचलित थी। 1829 ई से 1883 ई तक अमेरिकी सावजनिक जीवन म इसका वडा जोर रहा या और सभी शासनीय पदा पर विजयी राष्ट्रपति द्वारा अपने राजनीतिक दल के व्यक्तिया की नियुक्तियाँ की जाती थी। इस जूट प्रणाली के गम्भीर दुप्परि-णाम हुए 15 (:) प्रशासन म अक्षमता (mefficiency) का साम्राज्य न्याप्त हुआ था। (॥) राजकीय पदा की सत्या में बद्धि हुई थी। (॥) राजनीतिक भ्रव्टाबार न ब्यापक रूप धारण कर लिया था। (1v) नियुक्तियों को लेकर राष्ट्रपति व सीनेट में गम्भीर मनभेद एव द्व द्व उस्प न हो गये थे। (v) राष्ट्रपति एव अप विभागाध्यक्षा के समय एव शक्ति का अत्यधिक अपन्यय होने लगा था। पत्रधिकारिया का चयन कांग्रेसजन एव दलीय नेताओ द्वारा समुक्त रूप में किया जाता था। दला द्वारा जिन व्यक्तियो को नियक्त किया जाता था उनसे दलीय निर्वाचन कीए के लिए देतन का कुछ प्रतिशत निश्चित कर लिया जाता था। फलस्वरूप कमचारियो द्वारा अधिक वेतन की मांग की जाती थी। इस प्रकार लूट प्रणाली के अत्तगत दला की राज्य स अप्रत्यक्ष रूप से धन प्राप्त होता था। इसके अतिरिक्त इस व्यवस्था के अधीन जो कमचारी नियुक्त किये जाते थे वे पूरी तरह राजनीतिक इध्टिकीण म रंगे होते थे। तत्कालीन जनता नी हिट म राजनीति एव प्रशासन पृणित काय थे एव शायद ही कभी कोई राज्य इसना भ्रष्ट रहा हो जितना नि लूट प्रणाली के युग का अमेरिका ।19 क्षमता का अमाव, भ्रष्टाचार, घूसखोरी एव दलीय मानना की प्रधानता लुट प्रथा के कृत्सित दर्पार-णाम छे।

1880 ई म लूट प्रथा के विरुद्ध तीय जनमत वन चूका था। 1883 ई म सीनट न स्विवित सर्विस अधिनियम (The Civil Service Act) पारित किया था। इसे पारित करान म सीनेटर पिंडलटन का प्रमुख हाथ था। अत इसे Pendleton Act मी नहते हैं। इसके अनुसार—

¹⁸ Finer op at p 832

¹⁹ Never had a State been so debauched and worse still politics and administration fell into public contempt."—Finer Ibid, p 832

- सीनेट के परामश्य से राष्ट्रपति को त्रिसदस्यीय लोक-सेवा आयोग के गठन का अधिकार प्रदान किया गया,
- (2) लोक सेवा आयोग का यह कतव्य निर्धारित किया गया कि इस विधेयक को कियाचित करने के लिए आवस्यक नियमादि का निर्माण करके वह राष्ट्रपति का सहयोग प्रदान कर, तथा
- (3) सुप्रवासन के लिए वाछित परिस्थितियों के निर्माण, प्रत्याशिया की योग्यता के निर्धारण हुत खुली प्रतियोगी परीक्षामा की व्यवस्था, सेवा सम्बन्धी शर्तों एवं सवाबा की श्रेणिया के वर्गीकरण आदि के सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग को नियमादि के निर्माण का अधिकार प्रवान किया गया।

लेक्नि लूट प्रथा पूणत समाप्त नहीं हुई है। लोक सेवा आयोग म दोना दलों को प्रतिनिधिस्व दिया जाता है। राष्ट्रपति को अनेक महत्यपूज प्रशासकीय एव तकनीकी पदों पर नियुक्ति का एकाधिवार बना हुना है। 1905 ई में लोक सेवाआ में सुधार के लिए देश म एक बार पुन नागृति उत्पन्न हुई थी। लेकिन लूट प्रया को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सका। 1916 ई तक समम्पा आये पदा पर प्रतियोगी परीक्षानों हारा नियुक्तियाँ होने लगी थी। 1930 ई तक लूट-प्रथा प्राय पूरी तरह समाप्त हो सुक्तियाँ होने लगी थी। 1930 ई तक लूट-प्रथा प्राय पूरी तरह समाप्त हो सुक्तियाँ होने लगी थी। 1930 ई तक लूट-प्रथा प्राय पूरी तरह समाप्त हो सुक्तियाँ हो गय केवल कुछ उच्च पदी को छोडकर सभी शासकीय पदा पर नियुक्तिया लोक-सेवा आयोग के द्वारा ही होती है।

हरमन फाइनर क जनुसार अमेरिकी उच्च सेवा म योग्य कमचारिया के अमाव के दो निम्न कारण है प्रथम, प्रशासकीय श्रेणी या प्रशासकीय विश्व मण्डल (administrative brantinust) को कोई मा यता नहीं दी गयी है। प्रिटेन एव फार्स की उच्च प्रशासकीय विश्व मण्डल (विज्ञातां क्षेत स्वासकीय सेवां को मौति पूरी तरह प्रशासकों समर्पित प्रशासकी का निर्माण नहीं क्या जा सका है। संधीय कमचारिया के वर्गीक्रण म ऐसे प्रशासकीय अधिकारिया को कोई स्थान नहीं है। अधिकाश व्यक्ति जिह परीक्षा के मान्यम सं मतीं किया जाता है वे सेविन्यम एव विश्तीय मामलो तथा प्रशासकीय संगठन आदि के यियोधन होते हैं। उन्ह सामान्य प्रशासन अर्थात नीति का साध्य एव साधन के रूप मिर्माण म परामय का कोई अनुभव नहीं होता । द्वितीय, लोक सेवा की परीक्षात्रा म गहराई एव दार्धानिक या तार्किक संघय के किए स्थान नहीं है अपितु उसकी परीक्षार्य साध्य प्रशासन है। अत आवश्यकता हथ बात की है कि लोक-सेवाना की अहता सम्बन्धों आवश्यकत्तात्रां तथा विश्वा प्रणाली म निकट सम्मक होना चाहिए । हण्ड द्वा आयोग के सदस्यों को अमरिकी लोक सेवा व्यवस्था के प्रति काफी असतीय पा। आयोग का मत या कि कनिपट (jumor) वन्नानिक, तकनीची एव प्रशासकीय परा वी मतीं

²⁰ Finer op est, pp 842 43

के सम्बाध में न तो पर्याप्त प्रयत्न किया जाता है और न ही इस ओर पर्याप्त समय दिया जाता है।²¹

काइनर हूवर आयोग की इस सिफारिश को उचित नही मानत कि प्रायेक विभाग को लोक सेवा आयोग के अधीन अपनी आवश्यवतानुसार मर्ती की निजो योजना बनानी चाहिए। इस व्यवस्था से एकल प्रधासकीय सेवा का विकास नहीं हो सकेगा।²²

सपुक्त राज्य अमेरिका भं शासकीय कमचारियों को निजी व्यवसायों के कमचारियों की अपक्षा कम वेतन मिलता है अत योग्य व्यक्ति सरकारी सेवा म आकरित
नहीं होते हैं और जो आते भी हैं वे अवसर पाते ही शासकीय सेवा को छोंड देते हैं।
अमेरिकी लोक सेवा में सामायत 35 वप एव फुछ बेवाओं म 40 वप की आयु
तक के व्यक्ति प्रवेश पा सकते हैं। अप्य व्यवसायों म असफत होने पर अनेक व्यक्ति
शामकीय सेवाओं मं चले आते है। फलस्वरूप लोक सेवा म कुशतसा का अमान होता
है। इस व्यवस्था के अत्वन्त प्रशासकीय सवा को स्थायी जीवन-वृत्ति (permanent
Carrer) वनाने की प्रवृत्ति विकसित नहीं होती है।

अमेरिकी लोक सेवा मे सुधार की आवश्यकता है और इस सम्बाध मे निम्म सुकाव प्रस्तावित किये गये हैं ब्रिटेन एव का स की माति प्रशासकीय वर्ष का निर्माण किया जाय, योग्यतम एव बुद्धिमान व्यक्तियों को सेवा मे चुना खाय, लोक सेवा वा स्थायों जीवन वृक्ति के रूप मे विकास किया जाय, वेतन म बद्धि, प्रगति एव परो नित की उचित व्यवस्था की जाय। प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा विशिष्ट योग्यता की अपका सामाय पान की परीक्षा भी सी जानी चाहिए।

भारत मे लोक सेवा (Civil Service in India)

आधुनिक अब में प्रशासन का विकास ब्रिटिश काल से हुआ है। इस्ट इंग्डिया काम्मनी के सादन काल में कमचानी अप्रशिक्षित एवं अपर्याप्त वेतनमोगी होते थे। गवनर लॉड क्लाइंव न अपने दितीय कायकाल में इस सम्बन्ध में सुभार का प्रयत्त किया था। उसने कमचारियों की कम्मनी के साथ अनुन्ध (Contract) करने के सिष् बाध्य किया और निजी क्यापार तथा भागतीयों से उपहार लेने पर प्रतिवध साध किया और निजी क्यापार तथा भागतीयों से उपहार लेने पर प्रतिवध साथ दिये। फलस्वक्ण अनुज्ञ योग लांक सेवा (Covenanted Civil Scrivce) का विकास हुआ। सेकिन इन व्यवस्थाओं से कोई विशोध लाम नहीं हुआ। लांड कानवालित ने देश ने सम्मूण प्रशासन तन में व्यापार परिवतन किये थे। उचन परो पर अपना की एवं निम्न पदी पर मारतीया की निगुक्तियाँ की गयी। उसने कमचारिया ने निजी व्यापार करने पर प्रतिवध साथा दिया पर तु उनके वेतन ये विद्य करने तथा पर सारतीया की निगुक्तियाँ की गयी। उसने कमचारिया ने निजी व्यापार करने पर प्रतिवध साथा दिया पर तु उनके वेतन ये विद्य करने तथा परीव्या

²¹ Finer Ibid , p 843

²² Ibid

के लिए वरिष्टता के सिद्धा त को भा यता प्रदान की। लांड वेलेजली ने अपने समय में फोट वितियम म एक विवालय की स्थापना की विवाम प्रत्येक नवीन कमचारी को कम्पनी की सेवा म आने पर तीन वप तक मारतीय इतिहास, माथा एवं विभिन्न की सिद्धा सी जाती थी। लिंकन कम्पनी के डायरेक्टरा न इस विवालय को बाद म वद कर दिया और 1813 ई म हेलवरी (Halleybury) में एक विवालय को व्यापना को जो 1858 ई तक चलता रहा। भारतीय लोक सेवा के लिए मनोनीत व्यक्तियों को चार वप तक इस विवालय म शिक्षा दो जाती थी और किंटन परीक्षा होती थी। विवालय का प्रतिक्षण-त्वर जेंचा तथा अनुवालन कोर था। इस समय कम्पनी म सरक्षण प्रणाली (patronage system) प्रचलित थी। कोट आफ डायरेक्टर इस समय कम्पनी नियुक्तियों की जाती थी और विवालय के बाहते थे उसे नियुक्त करते थे। 1853 ई के चाटर अधिनियम के डारा सरक्षण प्रणाली को समान्त करते था। शिक्ष वे चाहते थे उसे नियुक्त करते थे। 1853 ई के चाटर अधिनियम के डारा सरक्षण प्रणाली को समान्त करते था। शिक्ष वे चाहते थे उसे नियुक्त करते थे। 1853 ई के चाटर अधिनियम के डारा सरक्षण प्रणाली को समान्त करते थे। 1862 इस समय के गयी। मकांत ने पूली प्रतियोगी परीक्षा का मुक्ताव दिया था और विदिश्व सत्तर ने उसे स्वीकार कर लिया था। मकांत ने लोक सेवा में मतीं के लिए किसी विवेष सिक्षा पर वल ने वकर केवल प्रवाशियों की मानसिक लागरुकता एवं क्षमता के परीक्षण पर वल दिया था।

1833 ई के चाटर अधिनयम द्वारा कम्पनी की सेवाओ मे भारतीयों के साथ समानता के व्यवहार का आस्वासन दिया गया था पर तु 1870 ई तक केवल एक भारतीय को ही कम्पनी की अनुबाधीय लोक सेवा म मर्ती किया गया था। भारतीय लोक सेवा की अधिकतम आयु सीमा 23 वय निर्धारित की गयी थी। इसे 1860 ई म 22 वप, 1866 ई म 21 वप एव 1878 ई म 19 वप कर दिया गया था। इतनी जल्पायु म भारतीया के लिए इगलैंग्ड जाकर प्रतियोगी परीक्षाजा मे भाग से सकना कठिन हो गया। अत भारतीय लोक सेवा म 1870 ई से 1914 ई तक केवल 14 मारतीय प्रत्याशी ही सफल हो सके। 1858 ई में कम्पनी के शासन का अन्त हो गया और भारतीय शासन काउन के अधीन आ गया। भारतीय लोक सेवा मे नियुक्ति के अधिकार भारत मात्री को प्राप्त हो गये। 1870 ई म भारतीयो को लाक-सेवा म नियुक्त करने के उद्देश्य से ब्रिटिश ससद ने विधि द्वारा भारत सरकार को इस सम्बन्ध म नियम बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया। सारत सरकार न इन नियम। के बनाने म 9 वप लगा दिये । इन नियमो के अधीन गवनर जनरल को समाज मे प्रति-िठत एव सम्मानित परिवारों के सदस्या को लोक सेवा में भारत मंत्री द्वारा प्रति वप की गयी नियुक्तिया के छठवें भाग के बराबर नियुक्त करने का अधिकार प्रदान किया था । फलस्वरूप सर्विधिक लोक सेवा (Statutory Civil Service) का विकास हथा।

लोक सेवा सम्बाधी इस व्यवस्था के प्रति मारतीय बनता म तीव्र असातोय या। मारत एव इगलैण्ड में एक साथ प्रतियोगी परीक्षाएँ करने की माँग श्री सुरे द्रनाय

बनर्जी द्वारा प्रस्तुत की गयी। अपने मत के प्रचार एव समधन हुत् उ हाने सम्पूण भारत का दौरा किया। इस समय तक अखिल भारतीय वाँग्रेस की स्थापना हो। चकी थी। काग्रेस ने प्रतियोगी परीक्षाओं की आयु सीमा बढाने एवं भारत तथा इंगलैंग्ड म साय साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था करने की गाँग की । एचीसन आयोग (Attchison Commission)--लॉड डफरिन ने 1886 ई

में चाल्स एचीसन (Sir Charles Aitchison) की अध्यक्षता म भारतीया की लोक सेवा सम्बाधी मांगापर विचार करने हेतु एक बायोगकी स्थापना की । बायोग ने (1) इगलैंग्ड एव भारत में साथ-साथ परीक्षा के विचार को अस्वीकार कर दिया, (2) अधिकतम आयु 23 वप कर देने का सुभाव दिया, तथा (3) अनुवाधीय एव गैर अनुवाधीय सेवाला के स्थान पर साम्राज्ञीय, प्रातीय एव अधीनस्य संवाला का वर्गीकरण प्रस्तावित किया । एचीसन आयोग का प्रतिवेदन एक लेख मान रह गया क्यों कि उस पर कोई कायवाही नहीं की गयी। भारतीय नागरिक सेवा के अतिरिक्त इसी बीच म अनेक नयी अखिल मारतीय सेवाओ की स्थापना की गयी। इनमे प्रमुख थी भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय स्वास्थ्य सेवा एव भारतीय शिक्षा संवा।

1909 ई के अधिनियम द्वारा मारतीया की माँगो को और अधिक बल प्राप्त हुआ। फलस्वरूप 1912 ई मे लोक सेवा मे भारतीय मांगोपर विचार हेतु एक आयोग की स्थापना लॉड इस्लिंग्टन (Lord Islington) की जब्दक्षता म की गयी। 22 परन्त् आयोग के प्रतिबदन देने के पून ही आ तरिक एन अ तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे अनक महत्वपूर्ण घटनाएँ घट चुकी थी। फलत लोक सेवा मे सुधार सम्ब धी अगला कदम 1918 ई की मॉण्टफोड रिपोट (Montford Report) के आधार पर ही उठाया गया।

मॉण्टफोड रिपोट की मुख्य सिफारिशे निम्नवत् थी

(1) मारत एव इगलण्ड म साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाएँ आयोजित की

जाये । (2) अखिल मारतीय सेवाओं के 33% पदो पर भारतीयों की नियक्ति की

जाय तथा इस सख्या मे प्रति वप 11 % की विद्व की जाय। (3) अखिल भारतीय सेवा के कमचारिया की उच्च पदो पर वेतन, पेशन,

अवकाश एव समुद्र पार जाने के मत्ते दिय जायें।

भारत शासन अधिनियम (1919 ई)--- मारत शासन अधिनियम (1919 ई) के द्वारा इन सिफारिकों को किया वित किया गया तथा वे दीय सेवाओं की मर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना को स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त लाक सेवाजा म साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धात की भी स्वीकार किया गया था

²³ थी गोपालकुष्ण गोखले इस आयोग के एक सदस्य थ । आयाग न अपना प्रतिवेदन 1915 ई म दिया था पर तु वह 1917 ई म प्रकाशित हुआ या ।

अत लाक तथा अन्य संवाजा म मुमलमाना को पृषक साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान क्या गया । तोक सेवा के यूरोपियन सदस्या के अधिकारी एव हिता की रक्षा का अधिकार गवनर को प्रदान किया गया ।

सी आयोग (Lee Commission) —1923 ई म लाड वी (Lord Lee of Farcham) की अध्यक्षता में एक अय शाही आयाय की स्थापना की गर्मी। उसके मुख्य सुभाव निम्नवत थे

(1) 1919 ई के अधिनियम में उस्लिखित लोक सेवा आयोग की तुर त स्यापना किये जाने पर बल दिया.

(2) अखिल भारतीय लोक संवाका की कुछ खेणियो—यया, शिक्षा, स्वास्त्य तथा इजीतियरिंग सेवा की सबक एव भवन वाखा को यारत मन्त्री के स्थान पर लोक प्रिय प्रातीय मन्त्रियों के लिय रण म हस्ता तरित करने का सभाव विया

(3) लोक-सेवा म 20% उच्च पदो पर प्रातीय नेवाओ के अधिकारिया की पदोत्रति करने एव सीधी भवीं म आधे मारतीयो एव आधे यूरोपियना को लेने का प्रस्ताव किया.

(4) पुलिस सेवा म यूरोपियन एव भारतीया का अनुपात कमश 5 एव 3 का रखा गया. तथा

(5) साझानीय (Imperial), प्रातीय (Provincial) एव अधीनस्य (Subordinate) श्रेणिया में लोक सेवा का वर्धीकरण प्रस्तावित निया।

भारत शासन अधिनियम (1935 ई)—इस अधिनियम द्वारा लोक सेवा प्रणाली में संशोधन एवं संधार के निस्नलिखित प्रयत्न किये गय थे

(1) मारतीय नागरिक (Civil) पुलिस एव स्वास्थ्य सेवाजा के अतिरिक्त रोप सभी सेवाएँ मारत मंत्री के नियन्त्रण से हटाकर गवनर जनरल एवं गवनरा के नियंत्रण में कर दी गयी।

(2) भारतीय नागरिक (लोक) सेवा कं पदो के अतिरिक्त सभी पदा पर विधानमध्यन का नियानम स्थापित कर दिया गया।

(3) सधीय एव प्रातीय लोक-सेवा आयोगा नी स्थापना पर वल दिया गया और यह व्यवस्था की गयो कि सधीय एव प्रातीय खासल भर्ती पद्धति, लियुत्तिया, पदीत्रति, स्थाना तरण, अनुसासन जादि ने सिद्धात्ता के निर्धारण म लोक सेवा आयोग से परामश लें।

(4) लोन-सेवाओ के यूरोपीय सदस्या के हितो की रक्षा ना दायित्व गन्ननर-जनरल एव गवनरा को प्रदान किया गया ।

. उपराक्त विवरण सं यह स्पष्ट है कि स्वतात्रता ने पूत्र 1919 ई तक लोक सेवाओं के मारतीयकरण की गति अत्यात चीमी थी। ०५० । जानुसक शासनत न

स्वत त्रता के पश्चात (After Independence)---मारत के स्वत व होन पर लोक सेवा के बहुत से अँग्रेज पदाधिकारिया ने पूर्वावकाश ले लिया एवं बहुत से मुसल मान सदस्यो ने पाकिस्तान जाने का निषय किया, फलस्वरूप यकायक उच्च लोक सेवको का अभाव हो गया । करीब 600 उच्च मारतीय नागरिक सेवा (I C S) के सदस्य कम हो गये। यही स्थिति भारतीय पुलिस सेवा म थी। इधर स्वतः त्रता के फलस्वरूप राजकीय दायित्वो मे विद्ध हुई थी और लोव-कल्याणकारी एव विमिन्न राजकीय दायित्वो को समालने हेत् प्रशिक्षित एव अनुमवी अधिकारिया की आवश्यकता थी। अत मारत के तत्कालीन गृहम त्री स्वर्गीय सरदार वल्लममाई पटेल ने अक्टूबर 1946 इ मे मुख्य मित्रयो का एक सम्मेलन नई दिल्ली मे आमितित किया जिसमे अखिल मारतीय प्रशासकीय एव मारतीय पुलिस सेवा के पुनगठन के सम्बंध मंत्रातों के मुरय मन्त्रियों की सहमति प्राप्त करन म ने सफल हा गये थे। तत्पश्चात मारत सरकार द्वारा एक विशेष मतीं मण्डल की स्थापना की गयी एव खुली प्रतियोगिता से बहुत से पदो के लिए व्यक्तिया की मर्ती की गयी। अब इनके प्रशि क्षण का प्रश्न सामने था। द्वितीय विश्वयुद्ध-काल म द्रिटिश विश्वविद्यालया म द्विवर्षीय प्रशिक्षण प्रणाली को अनेक ब्यावहारिक कठिनाइया के कारण स्थगित कर दिया गया या । अब देहरादून म एक अस्थायी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया । 1947 ई मे भारत सरकार ने नई दिल्ली स सारतीय प्रशासकीय सेवा (I A S) के लिए स्थायी प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की । 1955 ई म इस प्रशिक्षण संस्थान म अशकालिक (part time) प्राचायों के स्थान पर पूणकालिक (full time) प्राचाय एव उप प्राचाय (Vice Principal) की नियुक्ति की गयी। परन्तु इस व्यवस्था को भी जपर्याप्त एव अपूर्ण माना गया और मसूरी म राष्ट्रीय प्रशासन विद्यालय (National Academy of Administrators) की स्थापना की गयी । अब यही विद्यालय लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन विद्यालय के नाम स विरयात है।

लोक सेवा की प्रशासनिक समस्याएँ

लोक सेवा की प्रमुख प्रशासनिक समस्याएँ है मतीं (recruitment), परो नित्त (promotion), अनुसासन (discipline) एवं सेवा सम्बंधी अय शर्ते (जसे, पदावकारा, पेशन आदि)। अग्रिम पृष्ठों म इन पर विचार किया गया है। भर्ती (Recruitment)

द्यासकीय पदो पर भर्ती से ताल्यम निशिष्ट पदा के लिए योग्य एव उपग्रक्त व्यक्ति की बीज से है। भर्ती करने के लिए कमचारिया के पदा के विज्ञापन किये जाती हैं या मुक्त्य पदा के लिए उच्च प्रशिक्षित व्यक्तियों की खोज की जाती हैं। ¹⁴ प्राय सभी देशों म सरकारी पदा के लिए विज्ञापन निकाल जाते हैं एवं उनमें से योग्य

²⁴ Dimock Public Administration 1961, p 282

व्यक्तियों का वपन किया जाता है। सभी लोकतःशाय देशा में इस काय के लिए लोक सेवा आयोगा की स्थापना की गयी है। आयोग योग्य प्रत्यावियों के नाभा वा चयन करके शासन को भेज देते हैं और शासन उनको नियुक्त करता है। नूट प्रणाली अब प्राय पुणत समाप्न हा गयी है।

मतीं के दो तरीके हं प्रथम, सीधी मर्ती (direct recruitment), एव दिसीय, पदो नित (promotion) द्वारा मर्ती । यह दोनो तरीके ही हर देश मे प्रथ जित हैं । प्रत्यक्ष देश मे विभिन्न पदो के लिए पूर्विपिक्षत (prerequisite) योग्यताएँ निर्घारित कर दी जाती हैं । योग्यताएँ दो प्रकार को होती हैं (1) सामान्य (gene ral), एव (2) विधिष्ट (special) । सामान्य योग्यताला या अहताजा के अत्तपत नागिकता, आवास, लिम, अप्तु, आदि सम्ब धी अहताएँ होती है । विधिष्ट अहताजा के अत्तमत शिक्षा, अनुमुष्य एव वैधिक्तक मुल सस्य धी अहताएँ होती है ।

कमचारिया नी योग्यताओं की जाच करने के लिए परीक्षा एवं साक्षात्कार की पदित का अनुगमन किया जाता है। परीमार्ग वो प्रकार की होती है—प्रतियोगी (competitive) एवं अप्रतियोगी (non-competitive)। प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम में सभी उम्मीदकारा में हे बाह्यित स्वर के प्रत्यायियों की छाट नी जाता है एवं उनकी सापिक्षन स्थितिया (relative positions) का निर्धारण ियम जाता है। निम्म प्रकार नी परीक्षाएँ होती है (1) लिखित परीक्षा (written examination), (2) मौक्षिक परीक्षा (oral examination), (3) काय प्रदश्न (performance demonstration), एवं (4) शिक्षा और अनुभव का मृत्याक्रम (evaluation of education and experience)।

निवित परीक्षा का अनुगमन प्राय सभी देशों म किया वाता है। भारत व बिदेन में इन परीक्षाओं का उद्देश परीक्षाधिया की सामा य बुद्धि (general intelligence) एवं श्रेट्ठ झान (superior mind) का पता लगाना है। महाविद्यालया एवं बिद्यविद्यालया में पढ़ाये जाने वाले विषया म परीक्षा सी जाती है। प्राय यह विद्याल किया जाता है कि वा विद्यालय म अपनी बीद्धिक एवं अप श्रेट्ठता व्यक्त करता है कह सभी परिस्थितिया में अनिवायत सफल होता है। मारत म भी उच्च नागरिक (लाक) में को किए उन्हीं विषयों म परीक्षा भी जाती है बिनकी रिवार विद्यालया एवं विद्यविद्यालयों म दी जाती है।

संयुक्त राज्य अमेरिका म इसके विषरीत लिखित परीक्षा क द्वारा पद सम्ब भी विद्याप्ट ज्ञान का पता लगाया जाता है !

तिवित परीक्षा दो प्रकार की होती है निव पारमक (Essay type) एव लघु उत्तरात्मक बस्तुनिक्ट प्रणाली (Short Answer Objective type)। उच्च पदा के लिए निव धारमक परीक्षा थेट्ट होती है। लघु-उत्तरात्मक परीक्षा स केवल प्रत्याशी के तथ्य सम्बंधी नान का ही पढ़ा चलता है। मीधिक परीक्षा द्वारा प्रत्याची व व्यक्तिच आदि गुमा का अपात नतृत्व की क्षमता एव परिश्र बस का मूल्याकन निया जाता है। मीनिक परीक्षा का प्रयान प्रव प्रथम 1909 ई म इमलब्ड म निया गया था। इसके मुद्ध ममय परनात प्रशासकीय पदा पर चयन य तिए मीधिक परीक्षा अनिवाय कर दी गयी थी। मीसिक परीक्षा म प्रत्यासी की सतकता, बुद्धिमता, प्रत्यात्वनमति, चाम्न निषय एव निवम्राह्मता (sharpness) आदि प्रया का वता है।

मारत म प्रधासनिव संवा (1 A S) व निए 300 अरु, मारतीय विषय सेवा वे लिए 400 अब तथा आय व जीव संवाधा व लिए 200 अब साक्षात्वार के लिए निर्धारित है। मीनिव परीक्षा व सम्बन्ध म परस्पर विशेषी मत हैं। इसके दा प्रमुग दोप हैं (1) यह प्रधाली प्रमावास्त्रक, एव (2) वित्तनिष्ठ (subjective) है। अस्तित्व य सम्बन्ध म लोगा व मिन्न मिन्न मत हैं। क्रितनिष्ठ होन के कारण प्रस्थाशी की क्षमता वा आवत्तव वरत का यह अस्विषय अविवस्तानीय तरीका है। परितानिक स्वत्य देशा है। परितानी, मत, प्रवस्तहर एव कृषिम चातावरण म दिव यव अका म वदा अन्तर देशा गया है। जत फाइनर न साक्षारतार के स्वस्त्य य म निवन सुनाव दिय हैं

(1) साक्षात्कार की अवधि आधे पण्ड की हानी चाहिए ।

(2) साधान्कार म परीक्षा म पाइयत्रम म उल्लिखित प्रत्याची क हि क विषया पर हो बाद विवाद होना चाहिए।

(3) साधारकार एक पूरक परीक्षा क रूप म होना चाहिए।

(4) सारक्षार मण्डल भ व्यावसायिक सस्याना एव विश्वविद्यालमा क प्रधा सक मी हान चाहिए।

(5) साक्षात्कार निखित परीक्षा क बाद हाना चाहिए।

(6) विश्वविद्यालया के शिक्षका क प्रतिवदन पर विचार शरक ही अक प्रदान किय जान चाहिए।

(7) साक्षारवार क अका की सक्या घटावर अधिवतम 150 कर देती

चाहिए।²⁵

भारतीय तो सेवा म साक्षात्कार व 400 अक होत हैं। इसकी वहु आती चना की गयी है। समुक्त राज्य अमरिका म साक्षात्कार को अधिकाधिक बस्तुतिष्ठ बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। साक्षात्कार तेन बाता के द्वारा विशेष फान (rating forms) का प्रयोग किया जाता है एव सम्यूच बातों टेन रिकॉड को जाती है। इसके अजिरिक्त समृह साक्षात्कार की पद्धति वा भी विकास हो रहा है। इसम 10 12 प्रयाधियों को बात विवाद के तिए एक विषय दे दिया जाता है।

सोक सवाजी की मतीं का दायित्व लोक सेवा आयोग का है। ये अपने क्षेत्र म

स्वायत सम्पत्र होते है और सविधान द्वारा इसकी स्वायत्तता सरक्षित होती है। वे त्याचर राज्य र राज्य पाय स्थान का स्थान होते हैं। लोक सेवा आयोग के सदस्यों कार्यपालिका के नियंत्रण एवं हस्तक्षेप से मुक्त होते हैं। लोक सेवा आयोग के सदस्यों कारपालका माराच पण एक १००४व ० उम्म १०० १ । आहे ०वा नावार मारावका की निवृक्तियों मुख्य कायपालिका द्वारा की जाती है। विभिन्न देशा में लोक तेवा ा १९ वर्ष १९ जापार के संस्था के लोक सेवा आयोग के सदस्य राज्यपाली द्वारा निवृक्त किये जाते राजुरात पुर पार्टिक पार प्रवास प्रवास के अवस्थित का भी गठन कर सकते हैं। हैं। दो या अधिक राज्य मिलकर संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी गठन कर सकते हैं। ्रायोगो के लगमग आंचे सदस्य ऐसे होने चाहिए जो कम से कम 10 वप तक शासन नानाम कर सुके ही । इनका कायकाल 6 वप होता है या सबीय लोक-तेवा आयोग के सदस्य 65 वप एव राज्यों के लोक सेवा आयोग के सदस्य 60 वप की आपु तक ्र त्याप ०० पर प्राप्त के आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों को दुराचार के आरोप अपने पदो पर रह सकते हैं। आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों को दुराचार के आरोप पर सर्वोच्च यावालय की जाच एव प्रतिबंदन के आबार पर राष्ट्रपति उह उनके पद

न्निटेन मे लोक सेवा आयोग की स्थापना 1855 ई मे की गयी थी। इतर्व सदस्य सत्पा समय-समय पर बदलती वहती है। 1953 ई मे इसमे अध्यक्ष (जिसे प्रण से पृथक कर सकता है। अपुक्त (First Commissioner) कहा जाता है) के अतिरिक्त 5 सबस्य होते ? नाउंग (किटन के अल्पकातिक सदस्य होते हैं । 1961 ई में भी केवल 5 सदस्य थे। ब्रिटेन आयोग की सुरक्षा एव स्वत त्रता सम्ब थी कोई विशेष व्यवस्था नहीं है कि तु हेकों मे जो सुरक्षा आयोग को सविवान द्वारा प्राप्त हुई है वह त्रिटेन में दीवका परम्परा एव जनमत के प्रमाव से प्राप्त है। इनकी निवृत्तियाँ रानी द्वारा प्रधान के परामच सं की जाती हैं। प्रधानमंत्री लोक देवा के प्रमुख (ट्रेजरी के संपुक्त क सचिव) से इस सम्बंध में अनिवायत परामध करता है। जिटेन में लोक सेवा के सदस्यों की बतमान स्थिति का वास्तविक आधार विमिन राजनीतिक दलों का लोक क्षेवा आयोग की निप्पक्षता एव स्वतंत्रता की रक्षा के सम्बाध म एकमत होना है। बिटिश सोक सवा आयोग अस्पाची कमचारियो एव तकनीकी सेवा के सदस्यों का

सयुक्त राज्य अमेरिका के समीय लोक-सेवा आयाप म तीन सदस्य होते हैं जो अनिहिचत काल के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति हारा स्रोतेट की सहमति से निमुक्त किय चयन नहीं करता है। भागारत्य स्था स्थाप प्राप्त प्रमुख अमेरिको राजनीतिक दला के होते हैं। व्यवहार म दो सदस्य एक दल के एव एक सदस्य दूसरे दल का होता है। राष्ट्रपति सदस्या की परमुक्त कर सकता है। वमेरिकी लोक-तैवा आयाव भी जवनी ईमानदारी एव निष्प १५५५ १९ प्रमण १ । वजरूर स्वरूपन जनवन जा भागा १७११ एक वृहर साठन है। सता के सिए विस्थात है। अमेरिकी संघीय लोक-सेवा आयोग एक वृहर साठन है। बढ़े नगरा म इसके 13 जिला कार्यालय तथा 500 स्थायी परीक्षा मण्डल एव 150 रेटिंग मण्डल (Rating Boards) हैं । स्थानीय मण्डल अपने-अपने क्षेत्र म प्रतियोगी परीक्षाएँ आयोजित करते हैं ।

स्रोक सेवा आयोग के काय एव दायित्वा को तीन भागों म वर्गीकृत किया जाता है—(1) प्रत्याक्षिया का चयन, (2) पदो नित एव अनुसासन सम्य थी विवादा व अपीलों को सुनगर, तथा (3) वेतन निर्धारण, पद-वर्गीकरण, देवा रातों का निर्धारण तथा कमचारियों को सम्रा एव समुदाय, सम्यत्न एव प्रव थ, प्रशिक्षण एव सिनवार की समस्याओं सम्वर्धी अ वेयण करता।

ब्रिटन में लोक सेवा आयोग केवल कमचारियां के चयन से ही सन्विधत है। पदोनति एवं अनुसासन सन्व धो काय प्रत्येक विमाग एवं उसके कमचारिया द्वारा सम्पादित कियं जाते है। आयोग एक वग से दूबरे वग (Class to Class) मंपदो निर्तित से सी सन्विधत होता है। योप सभी काय कौपावार (Treasury) विमाग का वियित्त होते है।

सारत म लोक क्षेत्रा आयोगों का मुत्य रूप हो उपराक्त उस्लिखित प्रयम प्रकार के कार्यों अर्पोत् प्रत्याधियों के चयन से ही सम्बंध होता है। बिटन की तरह दूसरे प्रकार के काय विभागों द्वारा सम्पादित किये जाते हैं यहाँप इन गामलों में भी गों का परास्त्र नित्या जाता है। पदोन्नति, अनुसासन एवं क्षति-पूर्ति के मानला मंभी ग्रासन को आयोग से परामश नेता चाहिए। ततीय प्रकार के मामले मारत म आयोगों के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं।

सयुक्त राज्य अमरिका एव कुछ राष्ट्रमण्डलीय देवा म उपरोक्त उक्तिक्षित तीनो प्रकार के काय लोक-सेवा आयोगो का ही वायित्व है। अब अमेरिकी तोक सेवा आयोगो का कामक्षेत्र अपेकाइत आपक है। मारतीयो को ऐसा प्रतित हो सकता है कि अमेरिकी लोक-सेवा आयोग अनेक ऐसे कामों वो करता है वो कि ब्रिटर म ट्रेंबरी एव मारत म मृह मन्त्राव्य द्वारा सम्मादित किये वाते हैं। लोक सेवा के वायित्व एव कामों सम्बन्धी अमेरिकी विटकोण मिन है। वे लोक सेवा आयोग को सेविवय प्रशा सन से सम्बर्धित समी कामों को सम्यादित करने वाला प्रशासकीय अमिकरण मानते हैं। अमेरिकी लोक सेवा आयोग का प्रथम वायित्व अमरिका ये प्रशासत प्रशास के सम्यादित करने वाला प्रशासकीय अमिकरण मानते हैं। अमेरिकी लोक सेवा आयोग का काम योग्यता प्रणाली के प्राच्या स्व पुत्र प्रयोभ मे अमेरिकी लोक सेवा आयोग का काम योग्यता प्रणाली के माच्या से दुनगो को लोक सेवा से दूर रखना था। निषेधारणक कामों के कारण शीघ्र हो लोक-सेवा आयोगों मी तीव आलोचना होने सनी थी। और सेविवय प्रशासन (personnel admin) के स्वापनाथ अमेरिकी लोन सेवा आयोग ने पराधिकारिया सेवा असेविव लोक सेवा आयोग ने पराधिकारिया के बुताव के अतिरिक्त सेवाओं का वर्गोन्तरण, प्रशासकीय अधिकारियो ने वार्यो के विवस्त अपीलें सुनगा एव वृद्धावस्था (superannuation) सम्बन्धी मामवा को सम्यादित करना

प्रारम्भ कर दिया था। सेकिन संयुक्त राज्य बमेरिका मं इस दिप्टकोण के विरुद्ध ही म दिवा प्रारम्भ हो गयी। यह अनुभव किया जान लगा वि सेविवग सम्पर्याओं का ज्ञान विभागीय प्रवासन को ही ही सकता है और किसी बाह्य सस्या को इन मामलो ना पर्योप्त ज्ञान नहीं हो सकता। फलस्वरूप 1938 ई में प्रत्येक विभाग में सेविवग तिरोक्षण एवं प्रवन्य ज्ञाला सेविवग निर्वेशक (Director of Personnel) के अधीन स्थापित की गयी। इसके अतिरिक्त विदिश्च ट्रेजरी विभाग के स्थापना सम्मान (Establishment Division) या मारतीय गृह मंत्रालय के विभिन्न विभागों के सेविवग निर्वेशक की माति अन्त विभागोंय सेविवग प्रशासन परियद (Inter deve lopmental Council of Personnel Department) की स्थापना की गयी है। अमेरिका मं भी इस संस्था में अन्य वैशों की पढ़िता के अनुरूप परिवतन ही रहे हैं।

लोक सेवा आयोगा के द्वारा मर्ती की कुछ विद्वानों ने आलोचना की है। उनका तक है कि लोक सेवा आयोग प्रधान रूप म प्रत्याशी की बौद्धिक उपलब्धि को ध्यान मे रखकर उसका चयन करता है। यह लोक सेवक क दायित्वों को देखते हुए ठीक नहीं है। चुने गये प्रत्याशियों को शासन की नीतिया एवं कायकमी से संक्रिय सहानु-मात होनी चाहिए। इसे समापत लोक-सेवा (Committed Services) कहते है। भारत म भी आजकल यह विवाद चल रहा है और ऐसी मा यता है कि लोक-सेवा की प्रगतिशील एव समाजवादी कायक्रम से सहानुभूति नहीं है और अनजाने ही लोक-सेवा प्रतिक्रियावादी तत्वो से गठब घन कर बठी है। अत उपरोक्त विचारधारा ने समयकों का कथन है कि विभागाध्यक्ष को अपन विभागीय कमवारिया को चनने का अधिनार होना चाहिए एव वाद में इन नियुक्तिया की जांच लोक सेवा आयोगा द्वारा की जानी चाहिए। उन्ह केवल यह देखना चाहिए कि नियुक्तियाँ युनतम निधारित योग्यता तथा नियमानुकल हुई है या नहीं । डॉ एम पी शर्मा का मत है कि इस मत को पदि किमाबित किया जाय तो 'लुट प्रणाली' की पूनरावृत्ति हो सकती है।27 सयुक्त राज्य अमेरिका में आयोगा द्वारा तीन प्रत्याश्चिया को प्रस्तावित किया जाता है। शासन उनमें से एक को चुन लेता है। ग्रेट ब्रिटेन एवं भारत म केवल योग्यतम प्रत्याची का नाम ही प्रस्तावित किये जात है एव शामन सामा यत उन्हें स्त्रीकार कर लेता है। ब्रिटेन एव भारत म शासन द्वारा आयोगो की सिफारिकों की उपेक्षा करने पर उसकी तीत्र आलोचना की जाती है।

भारतीय मर्ती प्रणाली की निम्न आलोचना की वाती है। दाँ एपितव्यी के अनुमार भारतीय मर्ती प्रणाली पर्याप्त कल्पनाधील और आकामक नही है अपितु इसम सेवियग के अधिकारा की बहुत अधिक सुरक्षा की व्यवस्था है। ऐसा प्रतीत होता है मानो विनापन बकीलो द्वारा लिये गय हो, न कि किसी प्रशिक्षित जन सम्पक

²⁷ M P Sharma Public Administration in Theory & Practice, 197

अधिकारी या प्रचारक द्वारा । ²⁰ इसके अतिरिक्त परीक्षा पद्धति मी अद्यतिन ज होने मौसिक परीक्षा को प्रवसा की है परन्तु उसकी धारणा है कि साक शास्त्रीय बाते अधिक प्रद्धी जाती हैं । ⁸ ए डो भोरेवाला के अनुसार विभिन्न वेतनमाना के लिए अर्दी की पृथक पृथक पद्धिवाँ होनी चाहिए। ¹⁰ साक्षात्का भी विश्वसनीय नहीं है। शोडे समय क बातिलाप द्वारा प्रत्याक्षी का सहीं सम्मव नहीं है। इसके लिए विश्वस्ट मनोबज्ञानिक परीक्षण की आवश्यकता है अतिरिक्त लोक सवा आयोगां एवं विश्वविद्यालया के मध्य और निकट सम्मक अवश्यकता है।

प्रधासकीय मुधार आयोग (Administrative Reforms Commiss मी मर्ती प्रणाली के अनेक दोषा की तरफ संगेत किया है एवं उनक निव अनेक सुभाव दिय है—(1) प्रत्यक देवा के लिए पर्याप्त कमचारी होने चाहि पाच वप प्रच ही कमचारियों की आवश्यकता सम्बन्धी योजना का निर्माण चाहिए।(2) सभी अखिल मारतीय एवं पैर-तकनीकी क्षेत्रीय सेवाओं के लि ही सिमलित परीक्षा होनी चाहिए।(3) प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अधि आप होनी चाहिए।(4) प्रचम श्रेणों के उत्तीण स्नातकों को लोक स आकार्यत करने के लिए विशेष प्रतियोगी परीक्षायं आयोजित की जानी चाहिए। पर वर्गों के उत्तीण स्नातकों को लोक स आकार्यत करने के लिए विशेष प्रतियोगी परीक्षायं आयोजित की जानी चाहिए। पर वर्गों करण (Position Classification)

पद वर्गीकरण का अय उत्तरवायित्व के आधार पर पदों को एकतित व वर्गों में विमाजित करना है। समान क्तब्यों एव दायित्वों से सम्बिधत पदों को वग म रखा जाता है, मले ही वे विमिन्न विमागों से सम्बिधत हो। इसी क समस्त विधिक पद एक ही वग म हात हैं। उत्तरवायित्व के अतिरिक्त शैक्ष योग्यता, वेतन एव विमागों के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। लेकिन वर्गीकरण अधिक महत्व के नहीं होते हैं। वर्गीकरण पद का होता है, न कि प्र

वर्गीकरण के तीन प्रकार हैं (1) सेवा (Service), (2) श्रेणी (Cla एवं (3) पदत्रम (Grade)। सेवा वर्गीकरण का सबसे व्यापक प्रकार है।

बिटेन म 19वी सदी के अन्तिम 25 वर्षों मे समान सेवाओ का वर्गीक

²⁸ Paul H Appleby Public Administration in India, Report of Survey 1953, pp 11 and 29

²⁹ Ibid p 29

³⁰ A D Gorewala Report on Public Administration, 1951, p 63

³² Administrative Reforms Commission's Report on Person Administration, pp 40 45

प्रारम्म हुआ था। प्लेपेयर आयोग (Playfair Commission) एव रिडले आयोग (Ridley Commission) की सिफारिखी के आधार पर द्वितीय सम्माग लिएक सहायक, वालक लिएक (boy clerk) एव मध्यम वग (intermediate class) की स्थापना को गयी थी। मैनडोनस्ड आयोग (1914 ई) ने सभी सेवाओं के लिए सीम श्रीणा——विरिट्ठ लिपिक, सहायक लिपिक एव प्रशासकीय श्रेणी के निर्माण का सुमाव दिया था। परचु प्रथम विश्व युद्ध के कारण इस सम्ब च मे कोई कायवाही न की जा जा सकी। ह्वीटिक परिपय सम्ब धी समिति ने 6 श्रीणयों को लिफारिश की (1) प्रशासकीय, (2) कायपालक, (3) लिपिक, (4) सहायक लेखक लिपिक (writing assistant clerk) (5) आश्चलिपिक, एव (6) टाइपिस्ट। इसे कोयागार वर्गीकरण (Treasury Classification) भी कहते है। यह वर्गीकरण सभी सवाओं पर समान रूप मंत्री है। धम, युद्ध, वायु एव बा तरिक राजस्व सम्ब धी विमागा के अपने वर्गीकरण है। उपरोक्त कोयागार वर्गीकरण के अतिरिक्त वैज्ञानिक, तकनीकी एव अय वर्गीकरण है। उपरोक्त कोयागार वर्गीकरण के अतिरिक्त वैज्ञानिक, तकनीकी एव अय वर्गीकरण है। उपरोक्त कोयागार वर्गीकरण हो। स्वयोग स सम्ब धित अतिरिक्त वर्ग हैं।

सपुक्त राज्य अमेरिका मे 1923 ई में संवप्रयम लोक सेवाओं का वर्गाकरण किया गया है। सधीय कमवारियों को पाच सेवाजा में वर्गीकृत किया गया है (1) व्यावसायिक एवं वज्ञानिक (professional and ecientific), (2) लचु यावसायिक (sub professional) (3) लिपिक—प्रधासकीय एवं राजस्व सम्बंधी (clerical administrative and fiscal), (4) सरक्षकीय (custodial), (5) लिपिक या त्रक (clerical mechanical)। इन सेवाओं को वर्गा एवं वेतनमानों में विमाणित किया जाता है।

भारत में इंस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन काल म अनुब बीय एव गैर अनु-व धीय (covenanted and uncovenanted) संवाओं के रूप में पहला वर्गीकरण किया गया था। एचिसन समित (Auchison Committee) ने लेवाओं को साझा-शीय (Imperial), प्रातीय (Provincial) एवं अधीनस्थ (Subordinate) श्रेणिया म वर्गाञ्ज विया था। इस्लिंग्टन समिति (Islington Committee) ने साझानीय एवं प्रातीय श्रेणिया को मिलाकर एक साझाजीय सेवा नगाने और उस उच्च एव निम्न श्रेणिया में वर्गीञ्जत कर देने का सुभाव दिया। साझाजीय सेवाजों को बाद में भारतीय एवं कडीय सेवाजों की साझा प्रवान की गयी। भारतम जी द्वारा नर्ती किये गयं कमपारियों को भारतीय सवा तथा गवनर जनरल द्वारा मर्ती व मचारिया को कडीय सेवा कड़ा गया। इसके जितिरक्त संवाओं को राजपनित (gazetted) एवं अराजपनित (non gazetted) में वर्गीञ्ज किया गया है।

1930 ई के पश्चात मारत शासन के अधीन सेवाआ को अखिल मारतीय के द्रीय सवाओ मे वर्गीकृत किया गया है। अखिल मारतीय सवाओ से दो सेवाएँ मारतीय नागरिक सेवा (I C S Indian Civil Service) एव मारतीय विदय सेवा (I F S Indian Foreign Service) थी। के द्रीय सेवाया मं तमदा प्रयम, द्वितीय एव अभीनस्य तथा निम्म श्रेणिया (Class I, Class II, Subordinate and Inferior Classes) है। प्राचीय सवाए प्रयम, द्वितीय एव अधीनस्य श्रेणिया म वर्गी कृत हैं। 1947 ई कं पश्चात अधीनस्य एव निम्न श्रेणिया को त्रमद्य नृतीय एव चतुन श्रेणिया पुकारा जाने लया। आज कस मारतीय सेवाथा का वर्गीकरण निम्न वत हैं

- अखिल भारतीय सेवाएँ ।
 - (2) के द्रीय (सधीय) सेवा प्रयम श्रेणी ।
 - (3) के द्रीय (सघीय) सेवा—द्वितीय थ्रेणी ।
 - (4) प्रातीय राज्य सवा।
 - (5) विशेषज्ञ सेवाए।
 - (6) के द्रीय सेवाएँ-ततीय खेणी।
 - (7) के द्रीय सेवाएँ-चतुष श्रेणी ।

(8) के द्रीय सचिवालय सेवाएँ — प्रथम, द्वितीय, ततीय एव चतुव श्रेणियाँ। अखिल आरतीय सेवाएँ (All India Services)—सविधान के अनुकछद 312 के अधीन अखिल भारतीय सेवाओं की ब्यवस्था की गयी है। मारतीय प्रशास निक सेवा (I A S) एव भारतीय पुलिस सवा (I P S) का सविधान म स्पष्ट उल्लेख है। अय अखिल मारतीय सेवाआ के निर्माण का अधिकार मारतील ससद की प्राप्त है पर तु किसी नवीन अखिल भारतीय सेवा की स्थापना के लिए राज्य सभा को अपन 2/3 बहुमत से उक्त सेवा को जावश्यक घोषित करना चाहिए। 1962 63 ई में मारतीय अभियातिक सेवा (Indian Service of Engineers), भारतीय चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवा (Indian Medical and Health Service) एव मारतीय वन सेवा (Indian Forest Service) की स्थापना की गयी है। माच 1965 ई म दो अय सेवाबा--मारतीय कृषि सेवा तथा भारतीय शिक्षा सेवा--निर्माण का प्रस्ताव किया गया था। पर तु इनका निर्माण अधिकाश राज्यो की असह मित के कारण नहीं हो सका है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (I A S), मारतीय पुलिस सेवा (I P S) एव मारतीय विदेश सेवा (I F S) यह तीना भारतीय लोक (असनिक) सवा का उच्च वग हैं। इनकी मर्ती लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। मारतीय प्रशासन एव पुलिस सेवा के अधिकारियों को निर्धारित अशदान (fixed quota) के अनुसार विभिन्न राज्यों में बाट दिया जाता है। इसे राज्य केडर (State Cadre) कहते हैं।

प्रयम श्रेणी की के द्वीय सेवाओं के अधिकारी अपने अपने विमागों में उच्च परी पर काय करत हैं। के द्वीय सिववालय सेवा, भारतीय लेखा परीक्षण एवं लेखा सेवा, भारतीय डाक सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय प्रतिरक्षा लोक सेवा प्रमुख के द्वीय सेवाएँ---प्रथम थेणी---हैं।

भारतीय वर्गीकरण व्यवस्था की आलोचना की जाती है। मुख्य आलोचना यह है कि इससे सेवाओं में यग भेद उत्पन्न होता है। लोग सवाओं में एक प्रकार से जाति-प्रया जैसी क्ट्ररता का प्रचलन हो गया है जिसके कारण सहज सहयोगपुनक काय स बाधा उत्पन्न होती है। वेतन बायोग (1957-59 ई) ने इसके उपुलन का सुभाव दिया था । आयोग का मत था कि वर्गीकरण का कोई ऐसा व्यावहारिक उद्देश्य नहीं है जो इसक अमाव म पूण न हो सके। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण का कमचारिया पर अस्वस्थ मनोवनानिक प्रभाव पहला है। आयोग ने यह सुमाव दिया था कि लोक सेवा के समी सदस्या म यह मावना उत्पन्न की जानी चाहिए कि व एक सामान्य सेवा ने सदस्य हैं। वतमान वर्गीकरण इस मावना के विकास म बाघक है। 35 दूसरी आलाचना यह की जाती है कि प्रथम एवं दिलीय श्रेणी के भेद को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि दिलीय थेणी क रमचारियों के काय एवं दायित्व वहीं हैं जो प्रथम थेणी के कनिष्ठ वेतनश्रम (Junior Scale) के पदाधिकारिया को सौंप जाते हैं। कुछ विद्वान इन आलोजनाआ को स्वीकार नहीं करते । उनके अनुसार पद-वर्गीकरण के विना प्रशासन को वैज्ञानिक परिमापा सम्भव नहीं होती है। काय एव दायित्व के आधार पर कमचारिया म अतर होना चाहिए । पद वर्गीकरण का इस कारण त्याग नहीं किया जा सकता कि बुख कमचारी इसके कारण हीनता की भावना का अनुमन करत हैं। प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के मध्य नेद कायम रखन के पक्ष में यह तक दिया जाता है कि प्रथम थेणी के कनिष्ठ वेतनक्रम के अधिकारिया की मर्ती उच्च दायित्व वहन करने के लिए की जाती है और कनिष्ठ वेतनकम म काय करत हुए वे केवल उच्चतर दायित्वो को वहन करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। हितीय श्रेणी के पदाधिकारियों की मतीं चाहै वह पदो नित द्वारा हो या सीधे की गयी हो, उस पदकम (grade) से सम्बंधित नतव्यों की सम्पन्न करने के लिए की जाती है। इसका यह अथ नहीं है कि एक समय में किया गया पद-वाकिरण स्थापी होता है। लेक्नि उसम परिवतन तभी किया जाना चाहिए जबकि वह नय तथ्यो एव परिस्थितिया के कारण आवश्यक हो गया हो।

प्रशिक्षण (Training)

लोन प्रशासन में प्रशिक्षण का तात्यय ऐसी निया से हैं जिसस निर्दिप्ट दिशा में शासनीय कमचारियों की धमता सक्ति एवं बृद्धि तथा रुचि एवं मुख्यों को विक

³³ Commission on Enquiry of Emoluments and Conditions of Service of Central Government Employees (1957 59) Report, Governof India, p 562

700 | आयुक्तक शासनत न सित किया जासके। प्रतिक्षण एव शिक्षाम अत्तर है। प्रशिक्षण का क्षेत्र शिक्षास

सीमित होता है परातु दाना एक दूसरे सं सम्बाधित होत हैं। प्रशिक्षण का सम्बाध किसी एक कार्य से होता है जबकि शिक्षा व्यक्ति के सवागीण विकास सं सम्बाधित है। प्रशिक्षण के निम्म उद्देश्य हैं (1) कमचारी म विश्वसनीय कायक्षमता का विकास, (2) नमनीयता या लाच उत्पन्त करता. (3) मामाजिक चेतना क प्रति संजगता का

विकास, (4) उच्च दायित्वा एव कार्यों के उपयुक्त बनाना, तथा (5) मानसिक विकास करना और यह प्रावना उत्पन्न करना कि शासकीय कमचारी स्वामी नहीं होता अपितु जनता का सेवक होता है। ³⁴ पद्धति अविध एव स्तर की होट से प्रशिक्षण की पद्धतिया निम्नवत हैं (1) अनोषचारिक एव औषचारिक प्रसिक्षण (Informal and Formal

Training),
(2) अल्पकालीन एव दीघकालीन प्रशिक्षण (Short term and Long

term Training), (3) भर्ती के पूब एव बाद म प्रशिक्षण (Pre entry and Post entry

Training),
(4) विभागीय एव के दीय प्रशिक्षण, एव

(5) कला प्रशिक्षण एव पृष्ठभूमि प्रशिक्षण ।

ब्रिटेन⁵ मे एसीटन कमेटी (Assheton Committee, 1944) की निकारिय के अनुसार कोपागार प्रशिक्षण एव शिक्षा सम्माग (Treasury Training and Edu

के अनुसार कोषागार प्रशिक्षण एव शिक्षा सम्माग (Treasury Trauting and Co-Cation Division) की स्थापना की गयी थी। इस झाखा के दो मुख्य काय हूँ (1) सम्प्रण लोक सेवा के प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वय तथा निर्देशन करना, एवं (2)

विभिन्न प्रशिक्षण कायनमें को आयोजित करना । प्रशासकीय श्रेणों के कमचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था अधिकाल विभागा द्वारा ही की गयी है। नये कमचारी यादे समय के लिए वरिष्ठ विधिकारियों ने निरोक्षण में विभिन्न पदों पर काय करते हुए विभाग के कार्यों एवं दायित्वों के भान प्राप्त वरते हैं। कोपागार विभाग द्वारा एक सक्षिप्त कोस भी चालू किया आता

है जिससे कमचारी को गेवा सम्बाधी दाखित्वों का व्यापक नात हो सके। समी गिनट अधिकारी इसम माग लेते हैं। तये कमचारियों को दो या तीन सप्ताह के जिए परिचमी यूरोप के देशा के प्रशासन का ज्ञान कराते हेतु उन देशों म केज जाता है। 1015 वप के तेवा सम्बाधी अनुमव प्राप्त अधिकारियों म से कुछ को चुन कर

A Report of British Committee on the Training of Civil Servant
(Assheton Committee) 1944 p 6

(Assheton Committee) 1944 p 6 35 The Braish Civil Service B I ■ Pamphlet No R 4985, July 1961 pp 14 16

कोपागार विमाग के वरिष्ठ प्रश्नासकीय पाठचर्या के शिक्षण हेतु भेजा जाता है। एक सप्ताह का यह पाठचर्या सगठन तथा त्रव व की सामा य समस्याञ्चा से सम्बप्धित होता लोक सेवा | 709 है। इगलैण्ड म हेनले स्थित प्रशासनीय स्टाफ कालेज है। इसम उच्च पदाधिकारिया को प्रशिक्षण दिया जाता है। शासन तथा उससे सम्बिधत समस्यानी के अध्ययन के तिए कुछ अधिकारियों को एक वप तक का अवकाश भी प्रदान किया जाता है। प्रति-वय कुछ चुने हुए सचिवो एव समानपदीय वैज्ञानिक, व्यावसायिक एव कायपालक अधिकारिया के तीन आवासी 9 दिवसीय सम्मेलन होते हैं जिनम प्रव ध एवं सगठन सम्ब घी समस्याओं पर चर्चा की जाती है।

विटेन म कायपालक लिपिन एव अ य अणिया के कमचारिया के प्रशिक्षण का वायित्व विमाग का होता है। विमाग के प्रशिक्षण के अतिरिक्त इनके लिए विद्याप पाठयकम (course) भी प्रशिक्षण के क्रा पर आयोजित किये जाते हैं। ब्यावसायिक वैज्ञानिक एव तकनीकी कमचारियों को विभाग के याहर सस्यावा में प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त कीपागार विभाग ने प्रसिक्षण सम्बंधी सामा य नीति निर्धारित की है जिसके अ तयत कमचारियों को प्रशिक्षण के लिए भावस्यक सवतन अवकाश दिया जाता है। वरिष्ठ विमागीय कमचारिया द्वारा भी प्रवाध एव सगठन के सम्बाध म प्रशिक्षण दिया जाता है।

कमचारियों को सवा काल म शिक्षा प्राप्त करने की भी मुनिया हाती है। यह ह्वीटले परिपदो का दायित्व है। बहुत स विभाग अपने कमचारिया क तिए अव

त्य प्रमाणक समिरिका में लोक तेवा को विभिन्न महाविद्यालया या विस्व विद्यालया द्वारा सेवा म प्रवस के लिए तथारी करते समय प्रसिक्षण दिया जाता है। प्रवासन्त । अपने काल में ही प्रारम्म हो जाता है। ताना यत असे-र्रेषण्याचा शासकीय सेवा क इच्छुक व्यक्ति राजनीति विशान एवं सारू-प्रधासन म ारका न आक्रमान का किवेप रूप से अध्ययन करते हैं। विस्वविद्यालया हारा तक नीको पाठवनमो म हिस्तोमा प्रदान किया जाता है तथा स्वाहातीन निद्धांप मी दिया जाता है। विभिन्न विश्वविद्यालय नगर नियावन (Toan Planning) वजट-निर्माण, सावजनिक स्वास्त्य, पुनिस सासन वादि ने प्राप्तिम दत है। रमचारिता की प्रवशोत्तर प्रशिक्षण प्रदान करन की व्यवस्था विचित्तिक मन में ही होती है। अमरिक में अनक विस्वविद्यालय, असं जिनमा विस्वविद्यालय, होनड नाक-प्रधासन विद्यालय तिराक्ष्मण विश्वविद्यालय स्थित मैक्तवन क्ष्म द्वे निर्वोग्न विश्वविद्यालय स्थित मैक्तवन क्ष्म द्वे निर्वोग्न विश्वविद्यालय स्थ प्रतासन संस्थान विभिन्न पारंपन्तमा स मार्थित देव हैं। हीवड स्कूल के द्रवेश के नीति एवं निषयं करने (decision () र देव देव हैं। होवडे स्कूत के उद्भव मन विश्वविद्यासक के उत्तर () विश्वविद्यासक के उद्भव गत विस्वविद्यालय के स्तृत हैं निर्माण निर्माण वस दिया वाट है 1937 है म स्वाधित नेतन्त्र निर्माण निर्माण वन्त्र सी प्रियम दिया वाट है 1937 ई. म स्वाधित बुहिन्स हन्तुः (Boosings Institution) रूप ४४००

प्रसिक्षण मे बहुत सहायता दी जाती है। यह सस्या केवल प्रसासकीय काय प्रणालिय की ही शिक्षा नहीं देती वरन कमनारी की दूरदिवता एव विवेक सक्ति को विकत्ति करने का मी प्रयत्न करती है। विद्वविद्यालयों के जितिस्क सभी य अमिकरण, राज्य सरकार एव स्थानीय शासन की विशेष सस्याएँ प्रशिक्षण के काय में तभी हुई हैं। जुलाई 1958 ई में अमेरिकों कांग्रेस हारा शासकीय कमनारी प्रशिक्षण अधिनियम पारित किया गया है। इस अधिनियम द्वारा शासन को सभीय अमिकरणों (agencies) के प्रशिक्षण पर अपने कुल बजट का 10% तक घन व्यय करने का अधिकार विया गया है किकन कोई कमचारी एक वप से अधिक अविष के प्रशिक्षण कायक्रम म माग नहीं से सकता है। अमेरिका में अधिकाशत विवायतों की लोक सेवा म मर्ती की जाती है अत कायलिय के सगठन एव काय-विध से परिचित करान के लिए प्रशिक्षण आवश्यक होता है। इस प्रशिक्षण को व्यवस्था विशाग द्वारा वातो वाती है। ताक सवा आयोग मी अत विमागीय आधार पर प्रवस्था विशाग द्वारा वात्र पर प्रवस्था से साम विवाय प्रवस्था से साम दिवाय प्रवस्था से साम दिवाय प्रवस्था से साम होता है। इस प्रशिक्षण को व्यवस्था विशाग द्वारा को जाती है। ताक सवा आयोग मी अत विमागीय आधार पर प्रवस्था विशाग द्वार प्रवस्था प्रवस्था से सम्बाध में प्रविवाय करना है स्वाय प्रवस्था से साम स्वाय प्रवस्था से साम दिवाय के सम्बाध में प्रविवाय के सम्बाध में प्रविवाय करना है। सम्बाध में प्रविवाय के सम्बाध में प्रविवाय करना है। सम्बाध में प्रविवाय के सम्बाध में प्रविवाय करना कायोग साम स्वाय करता है।

भारतीय प्रशासन मे उच्च सेवाओं की व्यवस्था है । मारतीय प्रशासनीय सेवा भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षार्थिया (probationers) के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था, है। 1947 ई के पूर्व दिल्ली से एक प्रशिक्षण सस्यान या। कुछ वर्षी बाद उसे बाद करके मन्सूरी मे राप्ट्रीय प्रशासन अकादमी की स्थापना की गयी है। जब इसका नाम बदल कर लालवहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी कर दिया गया है। मारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों को छटवे वय जिलाधीश के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। प्रशिक्षण काल के दौरान उसे भारत-भ्रमण के लिए भी भेजा जाता है। अकादमी म प्रशिक्षण 9 माह का होता है। इसमे 5 माह तक मौलिक पाठ्यतम के विषयो म शिक्षा दी जाती है। मारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षायियों को जिला के विमिन्न कार्यालया से सलग्न कर दिया जाता है जिससे वह काम द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। करीब 18 माह तक वह अपर सचिव (under secretary) के रूप से सचिवालय म काय करता है। इस काल म मुख्य बल काम द्वारा प्रशिक्षण (job training) पर होता है। जिला एव सचिवासय स्तर पर विभिन्न पदा पर काय करने का अब नवीन अधिकारी को शासन के किसी विभाग म भी उत्तरदायित्वपूण पद को समालने योग्य बनाना होता है। विदेश सेवा के परिवीक्षार्थियों को मसूरी के राष्ट्रीय संस्थान म चार माह एव दिल्ली के अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल मे 4 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अति-रिक्त वे विदेश मात्रालय म 6 माह काय करते हैं, सनिक इकाइयो एव भारत की दशन-यात्रा करते है तथा किसी विदेशी भिशन में 1 वप तक काय करते है ताकि वे विदेशी मापा का अध्ययन एवं सामा य प्रशिक्षण प्राप्त कर सके।

भारतीय पुलिस सेवा (I P S) का प्रशिक्षण माउण्ट आबू स्थित के द्रीय पुलिस प्रसिक्षण कॉलेज म होता है एव दण्ड विधान दण्ड प्रक्रिया, अस्य शस्त्र एव ड्रिल तथा गेलनूद का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षणाधिया को सनिर नम्पनी भ भी कुछ समय के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। तत्वश्चात एक वय तक किसी जिला म परिष्ठ पुलिस अधिकारी की अधीनता म अनक अधीनस्य पदा पर काय करक काम का अनुभव प्राप्त करते हैं।

भारतीय त्तरा-परीक्षण एव तेरता तेवा का प्रधिक्षण िमना प विभागीय प्रतिक्षण स्कूल म होता हूं। आय-कर अधिकारियों का 18 माह मा प्रशिक्षण नागपुर म दिया जाता है। रत्तव मण्डल द्वारा वहीदा म एक स्टाफ क्रिज सचानित किया आता है। के द्वीय क्षित्रवालय सवा कं नवीन कमचारियों को दिल्ली स्थित सचिवालय मिराक्षण स्कूल म प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्ह सगठन एव प्रवाय तथा पद्धति, कार्यालय की कार्याविषया, विसीय नियमा एव विनियमों आदि म प्रशिमण दिया जाता है।

मारतीय प्रणानिक सेवा की प्रविक्षण प्रणाली की आलोचना की जाती है। यह कहा जाता है कि यह अपेक्षाकुत अधिव संद्वादिक है। क्या म पढ़ाये जाते वाले विषयों पर अधिक वल विधा आता है। इसके विपरीत, पयटन, न्यायालया, जिला परगना या ताल्लुका, तहसील के प्रणान क्यांत्रिया वे निरीक्षणों एव अभण पर अध्ययन हुतु अधिक वल देना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रविक्षण की आधुनिक तकनीकी प्रणात है। साति होनी चाहिए। अत भीतिक एव सामाजिक विषया वा ऐसा समिवत प्रशिक्षण कायकम होना चाहिए जिसने कि विद्यालय की क्यों को दूर किया या सके। इसके अतिरिक्त निवा मा निवा या सके। इसके अतिरिक्त निवा म नविव व पर्वान्त अधिक्षण कायकम होना चाहिए जिसने कि विद्यालय की क्यों को दूर किया या सके। इसके अतिरिक्त निवा म नविव व पर्वान्त अधिक्षण (post entry trauning) की पर्यान्त व्यवस्था होनी चाहिए। विमय पर्वाधवारियों के तिया नवीनीकरण पाटमभ की भी व्यवस्था होनी चाहिए। विमय पर्वाधवारियों के तिया नवीनीकरण पाटमभ की भी व्यवस्था होनी चाहिए। विमय पर्वाधवारियों के व्यवस्था होनी चाहिए। अनुमान समिति (1965 66 ई) द्वारा यह सिक्तारिय को पार्यो है कि मारतीय लोक सेवा के सदस्था का उद्याग एव वाण्यय से सम्वन्धिन मामलो का भी मान कराया जाना चाहिए जिससे कि नय अधिकारी विकासो मुख मारतीय अध व्यवस्था की समस्थाओं से परिचित हो सकें। 'अधिकाण काल म सुरम बल इस सात पर होना चाहिए कि प्रदेशकार्यों में सेवामाय उत्पन हो एव साहबी अथवा निकरसाही की प्रवत्ति व विद्याला में सेवामाय उत्पन हो एव साहबी अथवा

मन्त्रियो एव लोक सेवा के सम्बन्ध

लोक-सेवा एव मित्रया भ परम्पर क्या सम्बाध होने चाहिए व यह ससदीय व्यवस्था की एक प्रमुख समस्या है। बिटिश शासन प्रणाली की अनुमबहोन व्यक्तिया (amateurs) ना शासन वहा जाता है। मात्रीयल साधारण व्यक्ति (layman) और लाक सेवा ने सदस्य विशेषत (expect) होते हैं। मात्री राजनीतिय व्यक्ति हैं। वे

³⁶ Estimates Committee (1965 66) 93rd Report, 1966 pp 81 82

712 | जाधुनिक शासनत न

सावारणतया अपने विमाग के कार्यों से अनिभन्न होते हैं। उनसे यह आशा भी नही की जाती है कि उ हे विभागीय कार्यों का ज्ञान हो। अत वे अनुमवहीन होते हैं। व पेशेवर प्रशासक नहीं होते । इसके विपरीत, उनके अधीन काय करने वाले अ य विमा गीय कर्मचारियो—लोक सेवा के सदस्यो—को अपने विमाग के कार्यों का पूण ज्ञान हाता है। दीघकाल से प्रशासन काय से सम्बिधित होने के कारण वे विभागीय समस्याओ से परिचित होते हैं। वे अनुसवी होते हैं एवं मित्रयों की तूलना में स्यायी कमचारी कहे जाते हैं। सिडनी लो का कथन है कि 'ब्रिटेन का शासन अनुमवहीन व्यक्तियां का शासन है। अधीनस्य कमचारी प्रशिक्षित होते हे एव उच्च अधिकारी अप्रशिक्षित। अधीनस्य कमचारियो से उनकी योग्यता एव काय से परिचयात्मक प्रमाणपत्र की माग की जाती है लेकिन उत्तरदायी प्रमुख (मिनयो) से किसी प्रमाणपत्र की माग नहीं की जाती है।" "वित्त म त्रालय म द्वितीय श्रेणी के लिपिक का पद प्राप्त करने के लिए एक नवयुवक को अकगणित की परीक्षा मे अनिवायत उत्तीण होना ही चाहिए, पर वित्त मात्री अधेड आयुका ऐसा सासारिक व्यक्ति भी हो सकता है जो अका के विषय म अपनी उस जानकारी को भी विस्मृत कर चुका हो जो उसने ईंडन या आक्सकोड में प्राप्त की हो एव जो दशमलब के विद्या को कोपायार के हिसाब के सदम म देखकर उनका अय जानने के लिए उत्सक हो।" 8

मित्रयों की अनुमबहीनता एवं लोक सेवका की विवय योग्यता के कारण सहज ही यह प्रश्न उट्य न होता है कि उनके मध्य क्या सम्बय होने चाहिए। मधी राजनीतिन ध्यक्ति होते हैं। उह जनता की समस्याओं का नान होता है लिकन उनके पास इतना समय नहीं है कि वे प्रशासनिक क्षमता की पूणरूपेण जात्मसात कर सकें। इसके कई कारण ह

(1) मानी का वायित्य ही ऐसा है कि वह विशेषत्र की हर्ष्ट अर्जित नहीं कर सकता। वह नीति का निर्माता है। इस सम्बाध म वह पपन अधीनस्य कम चारिया (लोक सेवका) से परामश करता है। अत लोक सेवक का काय परामश देना एव नीति के निर्धारण के पश्चात उसका क्रिया वयन करना है।

³⁷ Government in England is government by amateurs. The subordinates are trained the superiors are untrained. We require some acquantance with the technicalities of their work from the subordinate officials but none from responsible chiefs. Sidney Low. Government of England, 1914, p. 201.

^{38 &#}x27;A youth must pass an examination in Arithmetic before he can hold a second class clerkship in the Treasury but a Chancellor of Exchequer may be a middle aged man of the world who has forgotten what hitle he ever learnt about figures at Eton or Oxford '—Sidney Low bld pp 201-202

(2) किसी मंत्री की किसी विसाग का अध्यक्ष विशेष ज्ञान या योग्यताके भाघार पर नहीं वनाया जाता है। लोक सेवा | 713

(3) मत्री का पद अस्यायो है अर्थात वह अपने विमाग का स्थायी अध्यक्ष नहीं होता है। ससद म उसके दल को बहुमत प्राप्त होने के कारण वह पद ग्रहण फरता है और जब तक ससद म उसका दल बहुमत म रहता है, वह पदारूड रहता है। बहुमत के समाप्त होने पर उसे पदत्याम करना पढता है। कोइ मानी एक ही विमान से सम्बिधत नहीं होता। उसे विभिन्न विभागा से मन्त्री का पद प्रहुण करना पहता है। इसके अतिरिक्त जम अनेक बलीय काय भी करने पडत है। म नी ससद का सदस्य है, वह ससद म उपस्थित रहता है प्रक्तों का उत्तर देता है एवं बहस म माग जेता हैं। इसके साथ साथ वह अपने निर्वाचन क्षेत्र का भी ध्यान रखता है। फलत उसक पास इतना समय होए नहीं रहता कि यह अपने विभाग सम्बंधी कार्यों म विशेष योग्यता अजित कर सक ।

विमाग वितरण के समय मित्रया को ऐसे विमाग दे दिये जाते है जिनका उह कोई ज्ञान नहीं होता। विश्वविद्यालय का प्रोफसर उद्योग म नी एवं वकाल युद्ध म नी नियुक्त किया जा सकता है। मन्त्रिया क्ष मध्य विभागो का वितरण उनके विभाग सम्ब सी हान या याग्यता के आधार पर नहीं किया जाता है अपितु राजनीतिक जीवन एव दल म उसके स्थान एवं स्थिति तथा उसकी सामा य प्रशासकीय पटुचा एव कायकुशलता के आधार पर किया जाता है। इसलैण्ड में लाड पामस्टन (Lord Palmerston) की औप निवशिक मत्री वनाया गया या पर तु ब्रिटिश साम्राज्य क जपनिवेशों का उसे कोई नान नहीं था। म नीपद ग्रहण करने पर उसने अपन अधीनस्य सहायक से यह प्रद्या था कि तक्सा म ब्रिटेन के उपनिवेश जहां जहां हैं उह वह बताये। स्पष्ट है म तियों को प्रधासकीय बारीकियों के लिए अपने लधीनस्य स्वायी सहयोगियों पर निमर रहना पडता है।

लीक सवा की कुछ जिनवाय विशेषताएँ हाती हैं, वे स्थायी होते हैं, दीप-काल तक विमाग स सम्बंधित होने के कारण विमाग के विशेषन होते हैं एवं राज-नीतिक मामला म तटस्य होत हैं। किसी दल का भी मिन्सण्डल हो व प्रण तटस्यता एव निष्पक्षता स अपने विमागीय मंत्री को परामझ देत हैं। उह इस यात की चिता नहीं रहेंती कि उनका परामद्य स्वीकार ही किया जाना चाहिए। यदि उनका परामद्र पहा रहेणा प्राचन प्रसम्बद्ध प्रचानार हो । जा जाला जाहर । जार जारा जाराज्य स्वीकार भी नहीं किया जाता तो भी वं उसे पूष निष्ठा म नियाजित परता हैं। यह लाक सेवा की तटस्थता विषयक त्रिटिस धारणा है। मंत्री एवं प्रसासक के सम्म सा पर सर बारेन किंगर ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है नि 'नाित ना निर्माण मित्रया का काय है एक बार नीति निश्चित होने पर तीक भवक का यह निश्चिम एक स्थाप काय है कि वह उस नीति का, चाह वह उसस सहमत हा अथवा नहीं, पूरी इच्छा त शिया है। गां पर प्रवासित सम्प्रते हैं एवं देस पर बाई निमाद नहीं हो सकरा

साथ ही साथ लोक सेवक का परम्परागत कतव्य यह है कि जब निणय किये जा रहे हो, वह अपने राजनीतिक अध्यक्ष के समक्ष सभी सूचनाएँ एव अनुभव दिना किसी भय या पक्षपात के उपस्थित कर दें, मले ही उसकी राय म ती के विचार के अनुकूल हो या प्रतिकृत ।"39 अत लोक सेवा को राजनीतिक हृष्टि से पूणत निरपेक्ष एवं तटस्य रहते हुए काय करना चाहिए । यही राजनीतिक तटस्थता ब्रिटिश लोकत त्रीय शासन का आधारभूत तत्व है एव उसके सक्षम सचालन के लिए उत्तरदायी है। 40 लाड मोरी सन के अनुसार लोक सेवा शासन के प्रति पूज निष्ठा रखती है। वे चाहे शासन की पस द करे या न करे लेकिन श्रेष्ठ यही है कि वे ऐसान कह। मैंने अपने लोक सेवक एव नगरपालिका अधिवारियो से सदैव यही कहा है कि "मै तुम्हारी राजनीति नहीं जानना चाहता । न तुम मुक्ते बताओ । मैं यह चाहता हूँ कि तुम्ह राजनीति का जान होना चाहिए परातु में चाहूँगा कि तुम दलीय राजनीतिज्ञ न बनी। तुम जी उचित समक्तो मुक्ते परामश दो एव मैं तुम्ह जो उचित समक्रुगा निणय दूगा। "पा ब्रिटिश लोक सेवा की तटस्थता का उदाहरण देते हुए उ होने कहा है कि 'पोस्टडाम सम्मेलन मे प्रधानमात्री चर्चिल के पश्चात जब एटली ने ब्रिटिश प्रधानमात्री के रूप में भाग लिया और जब पुराने लोक सेवको को उन्हें परामझ देते हुए देखा तो अमरीकी चिकत रह गये। " लाड मोरीसन के अनुसार जो मात्री एक व्यापारी की माति अपने जधीनस्यों के विचारों को नहीं सुनता है वह मूख होता है। उनकी बहस करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए पर तु निणय स्वय मानी को ही करने चाहिए। 15

42

Determination of policy is the function of Ministers, and once a 39 policy is determined, it is the unquestioned and unquestionable business of the Civil Servant to strive to carry out that policy with precisely the same goodwill whether he agrees with it or That is axiomatic and will never be indispute At the same time it is the traditional duty of Civil Servants while decisions are being formulated, to make available to their politi cal chiefs all the information and experience at their disposal, and to do this without fear or favour irrespective of whether the advice thus tendered, may accord or not with Minister's initial view -Sir Warren Fisher Permanent Secretary to the Treasury and Head of Home Civil Service, evidence given before the Royal Commission on the Civil Service (1929 31) (Minutes of Evidence HMSO 1931 p 1264)

The political neutrality of Civil Service is a fundamental feature 40 of British Democratic Government and is essential for its effi cient operation "-Report of the Committee on the Political Activities of Civil Servants, Cmd 7718 HMSO 1949, p 30

Lord Morrison British Parliamentary Democracy 1962, p 20 41 Ibid pp 19 20

Ibid . p 18 43

वहथा यह वहा जाता कि है चिक म त्री विमागीय मामला मे अनुभवहीन होते है और मित्रमण्डलीय, संसदीय एवं दलीय दायित्वा की सम्पादित करन के पश्चात उनके पाम प्रशासकीय कार्यों के लिए समय ही नहीं बच पाता अत बास्तव मे निणय उनके नाम पर लोक-सेवका द्वारा ही लिय जाते है। अत यह सुनाव रखे गये ह नि जिन विभाग के सम्बंध में मित्रया की जानकारी हा वही विभाग उन्हें सौपे जाने चाहिए। फा स नथा अन्य यूरापियन दशा मे सेना एव नौसेना विमामा के मन्त्री सैनिक व्यक्ति ही होत है। संयुक्त राज्य अमरिका न कायपालिका विसामा के अध्यक्ष के रूप मे विशेषज्ञा का नियुक्त किया जाता है। क्या न इसका ही अनुसरण ससदीय दशो म भी शिया जाय ? पर तु ससदीय देगो की समस्याएँ मिन है। ससदीय शासन उत्तरदामित्व के सिद्धान्त पर आधारित है। मित्रमण्डल सामाय निर्वाचन के समय जनता को दिये गये बचना के पालन के लिए बचनबद्ध होता है। अब ससदीय शासन के सदम म बेजहाट द्वारा उदध्त सर जॉज कानीयेल (Sir George Cornewell) ना निम्न कथन चरिताथ होता है-- "विभागीय काय करना म श्री का काय नही है अपित उसना काय तो यह देखना है कि विमाग ठीक प्रकार से काय करता है।' " रेमजे मक्डोनल्ड के अनुसार, "मिनमण्डल तो एक पूल की मांति है जो जनता को विशेषण से तथा सिद्धात को व्यवहार से सम्बद्ध करता है। वह विभाग की निर्दिष्ट दिशा मे अग्रसर करता है।"45 लास्की के शब्दों में सभी निषय मन्त्री के हाते है। लोग सेयका का काम तो मामला सं सम्बानित सामग्री एकतित करना है जिसके आधार पर ठीक निणय विया जा सके।46

लोक तेवा के सदस्या द्वारा मित्रया को अस्यधिक प्रमावित किया जाता है एव म त्रीगण सामा यत उनकी वाता को मानन के लिए बाध्य हात है। कहा जाता है कि म नीगण स्वायी अधिकारियों ने हाथा म यन्त्र की मौति हैं। "रेसवे म्योर का क्यन है कि म-नीगण 99% मामलों में लोक तेवा के सदस्या के विचारों को लोग स्ता है एवं उनकी सस्तुति पर हस्ताक्षर मात्र कर देते हैं। "इंगलिज को लोग सेवा के सदस्य म ब्यक्त उपरोक्त विचार मंगी समदीय दशा पर मागू हाते हं। परत रेमके म्योर के क्यन को उपहर्चेका स्वीकार मंदी किया जा सकता। म नी एवं

⁴⁴ It is not the business of Cabinet Minister to work his department. His business is to see that it in properly worked.—Sin George Cornewett, quoted by Walter Bagehot. The English Constitution, cited in V. D. Mahajan. op. cit., p. 50

^{45 &#}x27;The Cabinet in the bridge, linking up the people with the expert, Joining principle to practice'—Ramsay Mcdonald, cited lbid p 50
46 Laski Parliamentary Covernment in England, p 313

 ⁴⁶ Laski Parliamentary Covernment in England, p 31
 47 Laski Ibid p 313

⁴⁸ Ramsay Muir How Britain is Governed of cit, p 43

सम्बिधित स्थायी कमचारी के व्यक्तित्व तथा योग्यता पर दोना के सम्बध निमर करते है। यदि म नी याग्य, प्रमावशाली एव बीझ निणय बुद्धि से युक्त है तो वह इच्छानुसार काय कर सकता है, पर तु जिस म नी मे योग्यता एव काय को सममने की क्षमता नहीं होती है उन पर स्थायी कमचारियों का प्रमाव स्थापित होना स्वामाविक है। इमलैण्ड म लॉयड बॉज, चिंचत, रेमजे मैंवडोनल्ड ऐसे ही प्रमावशाली प्रयानम भी थे एव भारत म नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, गोविववल्लम पत, कृष्ण मेनन, कृष्णमाचारों ऐसे ही म त्री थे। शासन में लासकी के अनुसार, "राजनीतिक य न को लोकप्रिय इच्छा के निस्पृह एव निष्पक्ष बनुत्रव स सम्बद्ध करके शासन को गतिशोल बनाते है। लोकसेवको की सत्ता प्रमाव की है, शिक्त को नहीं। वे परिणामों को इतित करते है, आदश्च नहीं देते। वो भी निणय है वह मात्री का निण्य होता है।"

भारत मे म'त्री एव लोक सेवा मे सम्ब घ

भारत में मिनयो एव लोक सेवा के सम्बंध बिटिश प्रणाली पर आधारित हैं। भारत में मंत्री एवं सचिव सम्बंधी तीन प्रमुख विवाद विचारणीय हैं। प्रयम, टी टी कुष्णमाचारी तथा एच एम पटेल विवाद, द्वितीय, सुरक्षा मंत्री के रूप म कृष्ण मेनन सम्बंधी विवाद, एवं ततीय, गुलजारीलाल न वा तथा एत थी सिंह सं सम्बंधित विवाद।

टी टी कृष्णमाचारी वित्त मनी थे और एच एम पटेल उस विमाग के मुर्प सचिव। मूटवा नाण्ड से दोनो ही मनी तथा मुर्प सचिव सम्बंधित थे। टी टी कृष्णमाचारी ने छागला जाच आयोग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किय जाने पर वित्तमनी के पद से स्थानपन दे दिया था। आयोग ने जीवन बीमा निगम द्वारा मूढवा उद्योग म धन लगाने के निणय को धीझता म लिया याय निणय घोषित किया था। जीवन बीमा निगम वे यह सारा सौदा मूटवा को आधिक हिट से सहायता पहुँचान के लिए दिया था। छागला आयोग ने इस सौदेवाओं को धिषिक एव सामाय व्यापा रिक आचरण के विवरीत ठहराते हुए कहा था कि "यद्यपि यह सौदेवाओं जीवन बीमा निगम के निर्देशक कामय द्वारा मुख्य सचिव एच एम पटेल के निर्देश पर की योगी पिन पुत्र मनी को अपने सचिव कंकाय के लिए वर्षामा के लिए म थी को उत्तराविरव वहन करता हो चाहिए। "वह स प्रतिवेदन के प्रकारित होने के परचात ही प्री टी टी कृष्णमाचारी न पद स स्थानपुत्र दिया कि से प्रकार कर निया माम था।

⁴⁹ Laski op at p 313

⁵⁰ In my opinion, in any case it is clear that constitutionally the minister is responsible for the action taken by his secretary with regard to this transaction. It is quite clear that a minister must

थी कृष्ण मेनन के मुरक्षा म ती बनने पर सुरक्षा विभाग एकदम प्रकाश म आ गया था। कृष्ण मेनन ने सुरक्षा म तालय का पुनगठन एव उसके कार्यों का वर्गीव रण प्रारम्स कर दिया था। जनरन विभैया एव सुरक्षा म त्री म मेनाध्यत के चुनाव पर मतभेद उत्पन्न हो गये थे। जनरन विभैया एव सुरक्षा म त्री म मेनाध्यत के चुनाव पर मतभेद उत्पन्न हो गये थे। जनरन विभया एव स्वाना कृष्ण मेनन ने जानी एव सुमारमालम ने न चुन कर कौल को सेनाध्यक चुना। धिमया ने इस पर त्याचम दे दिया जिसे प नेहरू के कहने पर उद्योने वापस से लिया था। प नेहरू ने कृष्ण मेनन का समयन क्या। उनका कथन था कि हमारे सविधान व व्यवहार में नामरिक अधिकारी सवींक्ष है एव उन्हें रहना भी चाहिए। विनेहरू न कृष्ण मेनन की सुरक्षा विमाग में अचले काय की प्रशस्ता की। 1962 ई चीन द्वारा मारताय मना के पराजित होने पर मेनन का प्रशस्ता की। 1962 ई चीन द्वारा मारताय मना के पराजित होने पर मेनन का त्रीन विद्या चान कथा। अ नहरू के कायकारियों ने मी नेहरू पर मेनन का पदस्तुन करने के लिए दवाब हाला। अी नहरू न मनन का पदस्त्रीय कि पर मेनन को विद्याल किया पर तु नेहरू जी को ज न म इस के तीय विराध के कारण मेनन की मित्रमण्डल से हटाना पडा।

तीमरा विवाद श्री गुलजारीलाल न दा, एव श्री एल पी सिंह स सम्बध्वित है। गुलजारीलाल न दा गृह मानी थे। नवम्बर 1966 ई स सबदलीय गौरक्षा महा अभियान समिति क तत्वावधाल से एक बादोजन चताया गया। नवस्वर 6, 1966 ई का दिल्ली स एक जलून निकाला गया जा हिसक हो उठा। पुलिन की गीती ते 7 व्यक्ति मार य एव 148 व्यक्ति धायल हुए। साक्तमा एव एप्यसमा ने व्यक्तमा एव धार्यसमा ने व्यक्तमा एव धार्य हो निकास की तीत्र आलोचना की गयी। 8 नवस्यर को प्रधानम की ने श्री न दा को दिनाग परिवतन की सूचना थी। न वाजी न इस पर त्यापपन वै यिया। अपने त्यापपन म प्रधानम त्री ते उहान यह निकास की कि सिंपसालय से पूरा छहागेन निकास ने कि कारण नीति निर्धारण सम्बच्ची उनक्ति निणय अन्तिम नही होत थे। 'वा। आपन कभी यह कत्यन की है कि अपन को उप-करण प्रदान कि है उनमें में कक काम कर सकता हूँ।' उहोन दा उदाहरण भी प्रस्तुत कियं ''वयम, जलूत सम्बची निर्देश की श्रीत मंगने पर यह मन्त्री क प्राप्त ने प्रस्तुत कियं ''वयम, जलूत सम्बची निर्देश की श्रीत मंगने पर वह मन्त्री क प्रस

take the responsibility for action done by his subordinates "——Chagla Commission quoted by C P Bhambhari Bureaucracy and Politics in India, 1971, p. 135

⁵¹ Lok Sabha Debates, Sept 1959, Col 5857

² Bhambhars Bureaucrasy and Politics in India, op cit, Ch V pp 236 251

एकमाह परचात सचिव द्वारा भेजी गयी थी। द्वितीय, जलुस निकलने वाले दिन प्रात ही मात्री ने उप राज्यपाल, सचिव एव अाय अधिकारियो को व्यवस्था के सम्बाध म विचार करने के लिए बुलाया था और तब मुक्ते यह आस्वासन दिया गया कि सभी उचित प्रवाध कर लिये गये हैं।" इससे अधिक मात्री से क्या अपेक्षा की जाती है ? नादाजी ने इस घटना के पुत्र अपने विभागीय सचिव के परिवतन की भाग की थी जिस अस्वी कार कर दिया गया था। उनका कहना था कि सचिव महोदय ने बाहिद्रा सहयोग नहीं दिया अपित् दामित्वा के सम्पादन में वाधा उत्पन्न की। न दाजी के त्यागपत पर लोकसभा एव राज्यसमा मे ध्यानाकपण एव कामरोको प्रस्ताव उपस्थित किय गये। उस समय प्रधानमात्री ने मात्री एवं सचिव के सम्बाधी पर मत व्यक्त करते हुए कहा या कि 'नीति का अनुगमन किया जा रहा है या नही, यह देखनाम त्री का दायित्व है। सनिव द्वारा प्रस्तुत सुभावो का समयन करना या न करना म त्री का काय है।" वह सचिव को भिन्न निदंश दे सकता है। प्रधानमन्त्री से अपने सहयोगी मात्री की अपेक्षा लोकसमा के सदस्यों का पक्षपोपण किया था। यदि यह घटना किसी प्रमान शाली मात्री के साथ घटी होती तो मित्रमण्डलीय अस्थिरता की स्थिति उत्पत्न हो सकती थी। ससदीय शासन व्यवस्था की हृष्टि से मात्री बनाम सर्विव के सादमी म प्रधानमानी द्वारा साथी सदस्य मानी की उपेक्षा किया जाना उचित नहीं है। मंत्री व सचिव मं परस्पर विश्वास एव सहयोग होना चाहिए। यदि विसी मंत्री की किसी सचिव म विश्वास नही है तो उसे परिवतन की माग करने का पायोचित अधि कार है। सचिव को लोक सेवा की स्वस्थ परम्पराजा के अनुसार अपनी व्यक्तिगत अविच एव दृष्टि को विभागीय दायित्वा के सम्पादन म वाधक नहीं होने देना चाहिए। निस्स देह न दाजी सबैधानिक रूप से अपने विभाग क कार्या एवं नीतियों के लिए उत्तरदायी थे। इस घटना के सादम म यह विचारणीय है कि उप राज्यपाल एव गृह म पालय के सचिव ने दो भिन एव परस्पर विरोधी वक्तव्य दिये थे। प्रश्न यह है कि स्यायी लोक सेवा के सदस्या को वक्तव्य देने की क्या आवश्यकता थी जब कि उनसे नीति एव विमागीय काय के सादम म सावजनिक वक्तव्य देने की अपक्षा नहीं की जाती और न यही आञ्चाकी जाती है कि सचिव मात्रीकी उपेक्षा करते हुए विमागीय प्रस्तावा के रूप में म श्री से मित्र अपने वैकल्पिक प्रस्ताव म श्री की जानकारी के बिना ही म**ित्रमण्डल के अधिवेदाना मे उपस्थित करे,** जैसा कि उपरोक्त उल्लिखित गह सचिव ने किया था। लोक सेवाकायह बाचरण तो ससदीय व्यवस्था की जड ही खाद दता है। यह तो विभाग के राजनीतिक अध्यक्ष (भ त्री) एव स्थायी अध्यक्ष (सचिव) को प्रतिस्पर्धी समान स्थितियाँ प्रदान करन के समान है। सत्य तो यह है कि मात्री का निषय विभाग का निषय होना चाहिए। सचिव का वाय तो मात्री की परामश देना होना चाहिए। यदि सचिव को मात्री के विरुद्ध निषय करने वी परान्तरा का विकास होता है ता बह ससदीय व्यवस्था क उत्तरदायि व के जायाग्यूत सिद्धात को ही जब से जखाड फेकना होगा । क्या सचिव की उसके परामश के लिए आलोचना की जा सकती है ? नहीं ! मानी को ही उसका दायिन बहन करना पढ़ता है। सारत म नायां सिह विवाद के रेन्जे स्थार के इस कथन की पुष्टि होती है कि लोक सेवा के सदस्य मीं प्रमण्डलीय उत्तरदायित्व के आवरण में पनपत रहते हैं।" सारत में अधिकास सचिव आई सी एस या आई ए एस होते हैं। जब मी इस या के एक सदस्य में विवद्ध कोई काय किया जाता है, व मब एक गुट हो जाते हैं। यदि किसी सचिव के विवद्ध कोई काय किया जाता है, व मब एक गुट हो जाते हैं। यदि किसी सचिव के विवद्ध कोई क्या किया जाता है, व मब एक गुट हो जाते हैं। स्वत्य किसी सचिव के विवद्ध कोई क्या किया जाता है कि सारत म कमजोर एव सत्तरी से मुक्त विक्याजित मां प्रमाण जाता है। यह है कि सारत म कमजोर एव सत्तरी से मुक्त विक्याजित मां त्रमण्डल आई सो एस एव आइ ए एस अविकारियों के लिए बरदान है। राजनीतियों एव उच्च सोक सेवा म यदि अपितन गठवन्थन हो जाते हैं तो लोकतन्त्र के विषय वह अमिद्याप हो है। इत्तीय मतभेद लोक मचा को कीर अधिक समक्त बना हो हैं।

लोक-सेवा से सम्बन्धित अन्य बातें

प्राय सभी देशों से विरिट्ठता एव योग्यता के आधार पर पदोत्रित की जाती है। पिफतर के मतानुमार, केवल विरिट्ठता के आधार पर पदोत्रित का अब है—उच्च पदो पर अयोग्य एव असमय व्यक्तियों की निवृक्ति । इसमें कमचारियों म महरवाकाशों समान्त हो जाती है। जिल पदोत्रित ने लिए योग्यता (क्कारा) को महरव दिया जाना चाहिए। उच्च प्रयोग्यता (क्कारा) को महरव दिया जाना चाहिए। उच्च प्रयोग्यता एव शुणों के आधार पर ही पदोन्मित की जानी चाहिए। समुक्त राज्य अवेरिका में कमचारी की कायसमता का माप करना एक ख्यापक काय वन गया है। प्रयोग्य कमचारी को कायसमता का माप करना एक ख्यापक काय वन गया है। प्रयोग्य कर्मचारी को सेवा-अभिलेख एव सायसमता पाप (Service Records and Efficiency Ratings) रखा जाता है। बिटेन में 700 पीण्ड वार्षिक से अधिक वेतन पाने वाला की भवा का ही वार्षिक विवरण रखा जाता है। मासा यत परान्तिक किए परीमार्थ एव साक्षात्रका, कायसमता माप एव विमागाच्यक्ष या पदी नित मण्डस के निषय आदि पद्धिया का प्रयोग हिया जाता है। का साथ एवं विमागाच्यक्ष या पदी नित मण्डस के निषय आदि पद्धिया का प्रयोग हिया जाता है।

त्रमुक्त राज्य अमरिका म उच्च प्रशासकीय अधिकारियां एव विभागाध्यक्षां की पदो नीत परीकाओ एव कायक्षमता अभिलेखों के आधार पर होती है । काय क्षमता पद्धति का अमेरिका म विकास हुआ है तथा व्यापक रूप म उसका प्रयोग भी किया जा रहा है। हुवर आयाग के अनुसार यह पद्धति अत्यधिक जटिल एव

⁵³ Pfiffner Public Administration, pp 303 304

हुई है। आयोग ने कार्यक्षमता माप के स्थान पर योग्यता एव सेवा अभितेत भाप (Ability and Service Record Rating) के प्रयोग की सिफारिस की थी। इस सम्ब घ में अमेरिकी डाक विवाग की पढ़ित सवश्रेष्ठ तथा अनुकरणोय है। बाशिगटन के केवल कुछ प्रथम, द्वितीय एव ततीय श्रेणी के पीस्ट मास्टरों को छोड़कर सभी कम बारियों को प्रारम्भ में डाकियों एवं विधिकों के रूप म महीं किया जाता है। वे पार्ट शिक अवीक्षक के पद पर पदो नित करते हुए अर्थात विभिन्न पदों पर काम करते हुए

शिक अधीक्षक के पर पर पदो नित करते हुए अर्थात विभिन्न पदो पर काय करते हुए ही पहुँचत हैं।

ग्रेट निटेन में सेवा विवरण (Service Record) के आधार पर ही पदो नित होती है। प्रत्यक विमाग में पदो नित मण्डल होते है। मण्डल द्वारा कमचारियों के बापिक विवरण पर विचार किया जाता है तथा उसका साक्षात्कार होता है। तत्परचात ही पदो नित की सिकारिय की जाती है और विभागाध्यक्ष अन्तिम आदेश जारी करता है। क्षेत्र जर्थेण्डता के आधार पर ही पदो नित नहीं की जाती है। पदो नित मण्डल के निणय के विच्छ बयोल की आ सकती है। यदि राष्ट्रीय परिपद द्वारा स्वीकृत एवं अनुमोदित सिद्धान्त का उल्लयन किया गया हो तो विभागीय ह्वोटले परिपद किसी भी पदो नित पर विचार कर सकती है।

मारत म विभिन्न सेवाओं म रिक्त स्थानों में से निश्चित सस्था के पढ़ा के लिए मर्ती निम्न पद-कम (grade) एवं सेवा म काय करने वाले कमचारियों म स ही जी जाती है। उदाहरण के लिए प्रथम श्रेणी की सेवा म 55 प्रतिवृत्त व्यक्ति सीधी मर्ति से एवं दोष पदोनित से लिये जाते हैं। के क्रीय संविवासय के जुख उच्च पदो पर सीधी मर्ती नहीं की जाती है। मारतीय विदेश सेवा की 'ए साला म दह प्रतिवृत्त स्थान पदोनित से मर जाते हैं। द्वितीय श्र्यों की राजपत्रित सवाओं म 65 प्रतिवृत्त पद तृतीय श्रेणों के कमचारियों की पदोनित करके भर जात हैं। चुंच श्रूणी के कमचारियों की वहीं की स्थान म सर्वाय लोक स्था आयोग से परामय लिया जाना चाहिए। लेकिन सर्विधान के अनुचस्द 320 (3) के जनगत निमत नियमा के अनुसार नृतीय एवं चतुष्य श्रेणी के कम चारिया जी पदोनित आयोग के स्थापित कर के पदोनित आयोग के स्थापित की पदोनित आयोग के स्थापित कर स्थापित की पदोनित आयोग के स्थापित स्थापित की पदोनित आयोग के स्थापित की पदोनित आयोग के स्थापित स्थाप से स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित के साम पर योग्यता योग्यता एवं बरीयता हि साम यत योग्यता योग्यता एवं बरीयता (senority) या क्ष्यल वरीयता के आधार पर

विशेष विश्व है। विभिन्न विभाग के प्रोनिति सम्बयी नियम पुषक पृषक होते हैं। हिंदी में आती है। विभिन्न विभागा के प्रोनिति सम्बयी नियम पुषक पृषक होते हैं। विभिन्न कारा पदोलिति सम्बयी मुख नियम बनाव गय थे। योग्यता निर्धारण ने लिए सवा-अभिनेत्र, प्रति योगीय परीक्षा, समयता परीक्षा न परिखामा पर विभार विभा जाता है। विभागीय नियमा र अनुमार उच्च एवं मध्य स्तरीय पदा ने लिए योग्यता एवं निम्म परा के लिए उपस्टा एवं विभागीय नियमा स्वाता है। विभागीय नियमा मुस्ता नियमा स्वाता है। विभागीय नियमा मुस्ता नियमा मुस्ता नियमा मुद्दा निविद्य नियम स्वीद एक स्थला नहीं पांची आती। विस्



भ्रष्टाचार को रोकना एक कठिन नाय है। हमार देश म रिश्वत लेन व दन वाल दोनो दोषी होते हैं। फलत अप्ट अधिकारिया के विरुद्ध कोई सरक्षण उपलब्ध नही है। अनुच्छेर 311 की यायालय द्वारा की गयी व्याच्या के अनुसार शासकीय कम चारियों को भ्रष्टाचार के लिए दण्डित करना कठिन है। अब गासदीय कमचारियों को पद सम्ब थी बहुत अधिक सुरक्षा प्राप्त है। सविधान के 15वें सर्वोधन (1962 ई) द्वारा इस स्थिति म कुछ सुधार हुआ है तथा सरकारी कमचारियों के विरुद्ध आचरण सम्बन्धी जांच को शीध्रतापूबक निपटाने की व्यवस्था की गयी है।

व्यापक भ्रष्टाचार से जनता का प्रशासन म विश्वास हिल जाता है और राज नीतिक अस्यिरता उत्पत्र हो जाती ह तथा आर्थिक विकास के काम अवस्त्र हो जात हैं। सभी देशों म अप्टाचार भी एक्सानहीं होता है। ग्रेट ग्रिटेन एवं स्वीडन म भ्रष्टाचार नाममात्र का है।

भ्रष्टाचार का सीधा-साधा अथ यह है कि द्यासकीय कमचारी अपन दायित्व को सम्पादित करने के लिए धन या अय वस्तुएँ स्वीकार करता है तया अपने अधिकार के अनुचित प्रयोग द्वारा अवाद्यनीय लाम पहुँचाता है। भ्रष्टाचार के अनेक रूप हैं। केवल धन स्वीकार करना तो भ्रष्टाचार का एक रूप मात्र है। स्वय या अय अपने निसी परिचित या सम्ब धी के द्वारा यन लेना, अपने किसी सम्बाधी या आश्रित की किसी प्रमुख या प्रधान औद्योगिक प्रतिष्ठान म नियक्ति करा देना, राजनीतिक दल के लिए च दे के रूप में घन लेना एव सेवा निवत्ति के पश्चात किसी प्रतिष्ठान में ऊचे वेतन पर कोई पद ग्रहण कर लेना भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप हैं। बढे-बढे उद्योग पतियो एव व्यापारियो द्वारा मित्रयो एव शासकीय कमचारियो को विकित सुवि धाएँ प्रदान की जाती है, उदाहरणाय, वडे नगरो म अपने आवास गहो ने निवास की सुविधा प्रदान करना। यही नहीं, उच्च विमागीय अधिकारिया के दौरे का खर्ची सम्ब धित विमाग के निम्न कमचारी उठाते हैं। प्राय प्रत्यक सरकारी ठेके एव कम तथा विक्रय सम्बाबी मामलो म कुछ प्रतिशत कमीशन प्रत्येक सम्बाधित अधिकारी का निश्चित हुआ करता है, इसे 'हक' वहते है। कुछ शासकीय विभागा म मुख्य कापालय के लिपिका को विना धन दिये स्थाना तरण ही नहीं हो सकता। सरकारी कार्यालया में फाइल को आगे वढाने के लिए प्रत्येक स्तर पर रिश्वत की दरे निश्चित होती हैं। आज स्थिति यह है कि उचित काय के लिए भी रिस्वत देनी पडती है अ^{न्}यथा सम्ब िषत फाइल आगे बढती हो नही है। भारतीय के द्वीय सतकता आयोग (The Cen tral Vigilance Commission) द्वारा भ्रष्टाचार के विभिन 27 तरीको का उत्लेख क्या गया है। इन तरीको म सावजनिक घन एव सम्मत्ति के अनुचित प्रयोग से लेकर भूठे यात्रा मत्ते वसूल करना, पद का दुरुपयोग करना, उपहार ग्रहण करना एव झास कीय न्याटरा पर अवधानिक कब्जा करने तक के काय शामिल है।

समाजवादी देशा मे भी भ्रष्टाचार का प्रकीप है। प्रजीवादी लोकत प्रात्मक देशो के सदम मं अधिकृत सूचना उपलब्ध होती है परतु समाजवादी देशों के सदम म विस्तृत सूचना उपलब्ध ही नही है। नवोदित स्वतः त्र अफो एशियाई देशा में सर कारी प्रशासन त न म व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त है। मारत म इस समस्या के समा-धान के लिए विभिन्न आयोगा एव समितियों की स्थापना की गयी है। बगाल प्रशासन जीच समिति (1945 ई), रलवे भ्रष्टाचार जीच समिति (1953 55 ई) एव सथा नम समिति (1962 ई) इनम प्रमुख हैं। सयानम् समिति मे सात सदस्य ये जिनमे से पांच ससद सदस्य एव दो गह मात्रालय के वरिष्ठ अधिकारी थे। इस समिति का प्रति-वेदन मारत मे भ्रष्टाचार एव उसके निदान हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदनो मे सबसे अधिकृत प्रतिवेदन माना जाता है। मित्रया में व्याप्त भ्रष्टाचार इस समिति के क्षेत्राधिकार ने अतगत नहीं था । यही इसका सबस बडा दोए था । इसन अनेक महत्वपूण सुभाव दिये है, जसे, अनुच्छेद 311 को सशोधित किया जाना चाहिए जिससे अव्टाचार सम्बाधी मामला का शीध एव सरलतापुरक निवटारा हो सके, के द्रीय सतकता आयोग की स्थापना की जानी चाहिए और उसे निरीक्षण सम्बंधी व्यापक बक्तिया प्रदान की जानी चाहिए, शासकीय कमचारिया के आवरण सम्बाधी नियमो की इस प्रकार सशीधित किया जाना चाहिए जिससे कि पद निवृत्ति के पश्चात कोई शासकीय कमचारी निजी व्यापार एव उद्योगा म नौकरी प्राप्त न कर सके एव भारत सुरक्षा अधिनियम (1962 ई) को मी सद्योधित किया जाना चाहिए। सथानम समिति की इन सिफारिशा के आधार पर के द्र एव राज्या म सतकता आयोगो की स्थापना की गयी है। प्रशासकीय सुधार आयोग न लोकपाल एव लोकायुक्त की स्थापना का सुभाव दिया है। 1971 ई में इन पदाधिकारिया की स्थापना सम्बाधी विधेयक ससद में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन भारत मे भ्रष्टाचार उमूलन की इन संस्थायत व्यवस्थाओं का वाछिन प्रभाव नहीं हआ है।

लोक सेया एव राजनीति

लोक सेवको से जादश एव अनुकरणीय आचरण एव अनुवासन की अपेक्षा की जाती है। व शासन द्वारा प्रदत्त व्यापक अधिकारों का प्रयोग करते हैं अत यह बाध मीय है कि उनके आचरण सम्बची नियम हा विससे कि वे सत्ता का दुरुपयोग न कर सक । राजनीति से पृषकता अर्घात् पृण तटस्यता या निरमक्षता आधुनिक लोक सेवा कि एक अनिवास विपेचता मानी जाती है। यह लोक सेवा के आवरण सम्बची प्रधान नियम है। प्राय समी देशों म सामायत लोक-सेवाओं के आवरण सम्बची निम्म- विस्थित नियम प्रचलित है

 शासकीय कमचारी को राज्य के प्रति प्रक्ति रखनी चाहिए एव उ अधिकारियों के प्रति उचित व्यवहार करना चाहिए !

- (2) वे निजी व्यवसाय व व्यापार नहीं कर सकते हैं। उन पर अनैतिक एव गलत सस्यानो से सम्पत्ति अजित करने अथवा कज लेने पर कठोर प्रतिव ध होते हैं।
- (3) शासकीय, व्यक्तिगत एव पारिवारिक जीवन मे उन्हें स्वीकृत नतिकता के अनुसार जीवन व्यतीत करना पडता है, यथा---मारत मे शासकीय कमचारी एक से अधिक शादी नहीं कर सकता।
- (4) लोक-सेवको की राजनीतिक गतिविधिया---मापण, विचार, लेखन प्रका शन सम्बाधी आचरण-स्पष्ट नियमानसार होनी चाहिए।

इन आचरण सम्बाधी नियमा के कारण शासकीय कमचारियों की स्वतात्रता से नागरिक अधिकारों का सीमित हो जाना असम्मव नहीं है परतुलोक सेवा के दायित्वो को दखते हुए इसे अनुचित नहीं माना जाना चाहिए। भारत म लोक सेवा के आचरण सम्ब धी नियम पर्याप्त कठोर है। 1954 ई के अखिल मारतीयसेवा (आच रण) नियम इसका प्रमाण हैं। लोक सेवा के सदस्यो पर राजनीति मे सिक्य भाग लेने एव मापण, वक्तव्य व प्रकाशन द्वारा शासन की आलोचना करने पर प्रतिब ध है यद्यपि उह समाचार पत्र या रेडियो के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतानता प्राप्त है। आचरण सम्बाधी यह नियम तीन विवाद का विषय वन गया है। लोक सेवा की तटस्थता जहां लोकत न का एक सबल आधार है और उसकी क्षमता व दक्षता की हृष्टि से आवश्यक है, वही इस नियम के परिणामस्वरूप लोक सेवको का प्रयुद्ध एव जागरूक समुदाय राजनीतिक अधिकार से विचत हो जाता है। अत तोक सेवको सम्बाधी एक प्रधान समस्या यह है कि लोक-सेवा की राजनीतिक निष्पक्षता तथा उनके द्वारा सामा य नागरिक अधिकारों के प्रयोग के मध्य सम वय किस प्रकार स्यापित किया जाय। त्रिटेन की लोक सेवका की राजनीतिक कियावलाप सम्बंधी समिति (Masterman Committee) ने अपने प्रतिवेदन (1949 ई) म इस समस्या वा गम्मीर विश्लेषण किया है।55

इस समिति द्वारा लोक सेवका सम्बाधी निम्न तीन क्रियात्रा का उल्लेख किया गया है

(1) क्या लोक सेवको को ससद की सदस्यता के लिए प्रत्याशी होने का अधि

नार प्राप्त होना चाहिए ?

(2) क्या लोक सेवका को व्यक्तिगत रूप से अथवा लाक सेवा कमचारी सधी के सदस्या के रूप म राप्ट्रीय स्तर पर दलीय या ग्रैर दलीय राजनीतिक कार्यों म भाग लेने का अधिकार होना चाहिए?

⁵⁴ मारत म अखिल भारतीय संवा के सदस्यों को प्रति वय अजित की गयी अचल सम्पत्ति का विवरण देना पडता है।

⁵⁵ Report of the Committee on the Political Activities of the Civil Servants, 1949

- (3) क्या लोक सेवको को स्थानीय शासन में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए ⁷
- (1) ग्रेट ब्रिटेन म 1927 ई तक लोक सेवा के सदस्यो को ससदीय निर्वा-चनों में चनाव लडने की कोई स्वत बता प्राप्त नहीं थी। ससद की सदस्यता के लिए चनाव लड़ने के पुत्र उन्हें अपने पद से त्यागपन देना पडता था। लेकिन 1957 ई म विभिन्न विभागा के औद्योगिक कमचारिया को ससदीय सदस्यता के लिए चनाव लडने की स्वत नता प्रदान की गयी है। मास्टरमैन समिति (1948 49 ई) के द्वारा लोक सेवाआ को दो माना म वर्गीकृत किया गया है-(1) ऐसी सेवाएँ जिनके सदस्या द्वारा राजनीतिक कार्यां म माग लेने से सावजनिक विश्वास एव लोक-सेवा की क्षमता में सहज हास हो जाता है, और (11) ऐसी सेवाए जिनमें इस प्रकार की आहाका की कोई सम्मावना नही है। समिति ने प्रशासकीय, वज्ञानिक, तक्नीकी, व्यावसायिक, लिपिक श्रेणी के नीचे की सेवाएँ एव निम्न औद्योगिक एव दक्षता-प्रधान (manipulative) सेवाजा स अपर की सेवाजो के मध्य विमाजक रेखा खीच दी है। उच्च सवाजा पर राजनीतिक कार्यों म भाग न लेने का प्रतिव ध लगा हुआ है। समिति का तक या कि जिन अधिकारियों को नीति निर्माण, निर्देशन एवं उसके निया वयन सम्बाधी व्यापक स्वविवेकीय शक्तिया प्राप्त हैं तथा जि ह शासन के गोपनीय प्रपानों का निरीक्षण करने ना अधिकार है, उह ससद की सदस्यता के लिए प्रत्याशी होने पर त्यागपन देना चाहिए। अपने पद पर रहते हुए उन्हंससद की सदस्यता के लिए चनाव लडने का अधिकार नहीं है। इससे लोक सेवा में सावजनिक विश्वास के समाप्त हो जाने की हर सम्भावना है। इसके विपरीत, समिति के अनुसार जिन अधिकारियो का काय औद्योगिक एव प्रव धकीय प्रवृत्ति का है उन्ह राजनीतिक नतिविधियो म भाग लेने की पूर्ण स्वतः त्रता होनी चाहिए। समिति न यह भी प्रस्तावित किया था कि औद्योगिक एव प्रबाधकीय थेणियों के लोक कमचारिया को समदीय निर्वाचन काल मे प्रत्याक्षी होन पर एक माह का अवकाश दिया जाना चाहिए और निर्वाचित होने पर उन्ह पद से त्यामपत्र देना चाहिए। लेकिन ससदीय सदस्यता के समाप्त होने पर उन्ह पून अपने पद पर लौट आने का अधिकार होना चाहिए, यदि सम्बर्धित अधिकारी ने कम से कम 10 वय तक सेवा-काय किया हो।

भारत में शासकीय कमचारियों को पद त्याग के पश्चात ही संसद की संद-स्यता से लिए चनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है।

(2) लोक सेवका की अन्य राजनीतिक क्रियाओ से सम्बर्धित प्रस्त हैं— क्या शासकीय कर्मचारियो को राजनीतिक दलीय संगठन में किसी पद को धारण करना चाहिए? क्या उहे दलीय प्रश्नो पर वक्तव्य या दलीय प्रचार करना चाहिए? क्या शासन की जालोचना करते हुए उहं दलीय मामतो से सम्बर्धित लेख अथवा अप प्रचार सामग्री समाचार पत्रा म प्रकाशित करती चाहिए ? व्रिटन म शासकीय कमचारिया को दलीय सदस्यता ब्रहुण उरन एव मतदान करने की पूर्ण स्वतात्रता प्राप्त है अस्ति सासकीय रमचारिया का राजनीतिक विनाद स दूर रहने पर बल दिया गया है । उह धामशीय नीति की आनाचना भी नहीं बरनी चाहिए । ब्रिटन म सामशीय नवचारी द्वारा दलीय पद प्रहण करने, साब जनिय रूप ग शासन की नीतिया की जालायना करन या दल का प्रचार करने पर प्रतिबाप है। सनिन यह प्रतिबाध औद्यायिक बमवारिया पर लागू नहीं हान। उन पर कवल यह प्रतिवाध है कि व शामकीय कायानय म सवा कार्य क समय अधिकृत पोशाक को धारण करक दलीय प्रचार न नाय नहां कर सकत । मारत म नाई शास वीय कमचारी उपराक्त उस्तिखित राजनीतिक बार्यों म माग नहीं ले सकता यद्यपि उन्ह राजनीतिक दल की सदस्यता ब्रह्म करन एव इच्छानुसार मतनान करने की स्वतः त्रता प्राप्त है । मास्टरभन समिति न गर-दलीय मामला पर शासकीय कमवारिया यो व्यक्तिगत रूप स सावजनिक हित म अपन मत को प्रशट करन को स्वतापता का समयन किया था। लेकिन समिति न इस सादम म भी बुछ सुभाव दियं थं एवं उनके पालन पर यल दिया था, जसे दासकीय कमवारी का अपन विमाय के राजनीतिक कार्यों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, उसे सम्भना एवं वाद विवाद म माग सने के लिए विमागाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त करनी चाहिए, बाद विवाद म उसका सम्बाध केवल सच्या स ही होना चाहिए, उसका आचरण सर्यासत होना चाहिए एव पद सम्बाधी गोपनीय व्यवस्थाओं (Official Secrets Acts) का उस ध्यान में रहना बाहिए।

(3) येट दिटेत म दासकीय नमकारिया को 1909 इ. से स्थानाय वासन म विमागाध्यक्ष की अनुमति से माम लें। वा अधिवार प्राप्त है। आस्टरमन सीमित ने 1949 ई. म इस व्यवस्था को आगायी 5 वर्षों तन वायम रखते एवं तत्रवात रिधति से पुनिव्वार का सुनाव दिया था। तारत म 1919 ई. कर्य प्रायकीय कम-चारिया को स्थानीय सस्थाआ के निर्वाचनों म माग लेंन का अधिकार प्राप्त था। विकित नये नमस्थालिका एवं अय स्थानीय सासन सम्ब भी अधिनियमा के अन्तगत सासकीय वमकारियों को स्थानीय निकाय की सदस्यता के लिए अयोग्य पीरित कर

दिया गया है।

लोक सेवको से सम्बाधित एक अस महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि सासकीय कम चारिया एव सासन के मध्य क्या सम्बाध होने चाहिए ? द्यासन को आदय जातिक (Employees) की भूमिका निभानी चाहिए एव उसका यह क्तव्य है कि वह शास कीय कमचारिया की निजाइयों के निवारणाय उचित व्यवस्था करे। क्या सासकीय कमचारियों को समुदाय के निर्माण तथा इंडताल करने के अधिकार प्राप्त होने चाहिए ? सासन एव उसके कमचारियों के मध्य उत्पन्न विवादों का हल किस प्रकार किया जाना चाहिए ?

समुदाय के अधिकार (Right of Association) में तीन प्रकन निहित हैं क्या सरकारी कमचारी अपने समुदाय बना सकता है ? क्या यह समुदाय किसी न्त्रा प्रकार कर्मा प्रमुचन पत्त सम्बद्ध ए प्रवास वह प्रमुचन स्था प्रमुचन पत्त सम्बद्ध है है विभिन्न देशों म इस सम्बद्ध में मिन बार जानगात्वच र राज्य नारहा घरा हु । त्वा न वचा है। प्रेट द्वित में कमबारियों को कमबारी सर्घ (Service Association) बनाने की पूण स्वत वता है तथा वे इन सघी के सदस्य भी हो सकते हैं, बाह ये सप सासन डारा मा यता प्राप्त हा अथवा नहीं । उनके ये कमचारी सघ ए। नाव प्राप्त कर के भी सदस्य ही सबते हैं। एक प्रक्त यह भी है—बया कम कारों सम क्सी राजनीतिक दल से भी सम्बंधित हो सकते हैं ? ब्रिटेन मे केवल डाक कमवारी सब श्रम दल से सम्बाधत है। अ व कोई कमवारी सब किसी दल से सम्ब ियत नहीं है। इस सम्बंध में निरिचत नियम यह है कि शासकीय कमचारी सघी हुत्य अपना कीप राजनीतिक लक्ष्यों के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। संगुक्त क्षाच जाना करते प्रतिसारण प्रतिस्था का स्वत्य होते. का राज्य अमेरिका में सरकारी कमचारियों को अपने कमचारी संघा का सदस्य होते. का अपन नगरपार है। लेकिन इस सम्बन्ध म शत यह है कि ऐसे सप अपने सबस्या की कारणार काल एर पारणा वर्ष पारण काल काल प्रतिस्था काल प्रतिस्था काल प्रतिस्था काल प्रतिस्था स्थापित स्थापित स्था हुडताल की प्रेरणा नहीं दे सकेंगे। अस्तुता राज्य अमेरिका म सरकारी कमचारी सघी २-४४) वर्ष वर्ष के प्रतिवत वम तक ही सीमित कर रखी है। मास्त मे सरकारी ने अपनी सदस्यता कुछ निश्चित वम तक ही सीमित कर रखी है। मास्त में सरकारी व करा। अभ्याप उल स्थापक कर्म संगठना (Service Organisations) के ही सदस्य वन सकते है। यह मा यता चासन द्वारा सगठन की स्थापना के 6 माह के भीतर भग पर्णा १ , पर ना पात कार्य किन अर्तो के पूर्ण किये जाने पर ही इन सेवा प्राप्त हो जानी चाहिए। सासन डाय निम्न अर्तो के पूर्ण किये जाने पर ही इन सेवा सगठना को मा यता प्रदान की जाती है (1) ऐसा कोई ज्यक्ति इन सगठनी का सदस्य नहीं हो सकता जो धासकीय कमचारी न हो। (2) सगठन की कायकारिणी का चुनाव सदस्या में से ही होना चाहिए। (3) सप द्वारा क्सिी सदस्य के व्यक्तिगत मामले का समयन नहीं किया जाना चाहिए एव (4) सेवा समठनो का कोई राज-मीतिक कोप नहीं होना चाहिए और न उसके द्वारा किसी राजनीतिक दल या विचार का प्रवार ही किया जाना चाहिए। स्पष्ट है, भारत म शासकीय कमचारिया के सेवा सगठनों सम्बाधी नियम कठोर है।

प्रश्न यह है कि क्या शासकीय कमचारी को हडताल का अधिकार दिया जाय ? ग्रेट ब्रिटेन मे शासकीय कमचारी ढारा हुडताल करना कोई दण्डनीय अपराध हडताल का अधिकार नहीं माना जाता, वहां हुडताल के लिए शासकीय कमचारी के विष्ट केवल अनु ्रासनात्मक कायवाही ही की जा सकती है। व्यवहार में बेट विटन में सरकारी कम-चारियो द्वारा हडताल कम ही की जाती है और आये दिन वे हडताल को घमकी भी

⁵⁶ Refer to Sec 6(e) of the Lloydla Follete Act of 1912

नहीं देते है । संयुक्त राज्य अमिरका में सरकारी कमचारिया द्वारा हडताल करने क कातून द्वारा प्रतिब घ है। टाफ्ट-हाटले अधिनियम (1947 ई) द्वारा यह प्रतिबय शासकीय कमचारियां पर स्थापित किया गया है तथा हडताल करने पर शासकीय कर्मचारियों को सेवा से पदच्युत करने या तीन वय तक निप्कासित करने का दण्ड दिया जा सकता है। 1955 ई म काँग्रेस ने एक अप विधि द्वारा सम्बंधित दण्ड व्यवस्था को और कठोर बना दिया है।

भारत में ग्रेट निटेन की यांति शासकीय कमचारियो द्वारा हडताल विधि द्वारा निषिद्ध घोषित नहीं की गयी है। अत हडताल सं केवल अनुसासन भग होता है। के द्वीय लोक सेवा आचरण नियम (1955 ई) के अन्तगत शासकीय कमचारिया के हडताल करने पर प्रतिव ध है नेकिन यह व्यवस्था केवल गैर-औद्योगिक कमचारिया पर ही लागू होती है। रेलवे कमचारियों के अलावा अन्य औद्यागिक कर्मचारिया पर यह लागू ही नहीं होती है। आस्ट्रेनिया, जापात एव स्विटजरसण्ड म शासकीय कमजारियो द्वारा हटताल भैर कानूनी है। आस्ट्रसिया मे तो यह रण्डनीय अपराध है और हडताल करने पर कमचारी का सेवा से निप्कासन का दण्ड तक दिया जा मनता है। कनाडा में स्थिति पूणरूपण स्पष्ट नहीं है। कनाडा के ब्यूबक प्रांत मे प्रत्येक परिस्थिति म शासकीय कमचारिया को हडताल पर प्रतिव च है। कास ही केवल एकमान महत्वपूष पश्चिमी देश है जिसम शासकीय कमवारिया की हडताल का अधिकार प्रदान किया गया है।

विरव के अधिकाश देशा में शासकीय कर्मचारिया द्वारा हदताल का समयन मही किया जाता है ययोकि जामकीय कर्मचारिया द्वारा हडताल का अय उसी जनता को पिस्तील विखाना है जिसकी भेवा करना उसका प्रधान वाग्रित है। सरकारी कम चारिया द्वारा हडताल करन पर जनता के हिनो का हमन होता है और समाज म अध्यवस्था व अद्याति उत्पात हो जाती है। लेकिन कुछ विचारक सभी सरकारी कम चारियों को श्रीमक सगठन सम्बाधी अधिकार देन का समयन करत हैं। उनक अनु सार यही एकमान वह अस्त्र है जिससे श्रीमक दासता से मुक्त हो सकता है। यह स्वी कार करना पहेगा कि उग्र हडताली तरीका का शासकीय कमचारियो द्वारा प्रयोग अवाद्यनीय है। अत यह आवश्यक है कि शासकीय कमचारियों को अपनी कठिताइयों को दूर करन के लिए किसी मधीनरी या व्यवस्था के निर्माण का अधिकार होना चाहिए। ग्रेंट ब्रिटेन म प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात ह्वीटसे समितियों का निर्माण इसी उद्देश से किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ह्वीटले समितियों के सहस्य कोई व्यवस्था नहीं है और वहाँ शासन तथा उसके कमचारिया के मध्य उत्पन विवादा का विचार विमश्न से हन करने के लिए किसी सस्या का विकास नहीं हुआ है, अपितु अप तरीका का विकास हुका है। मारत म 1957 ई म स्टाफ समितिया की स्थापना की

गयी । 1960 ई म मारत सरकार ने स्टाफ समितियों को ह्वीटले सिमितियां के समकदा लान का प्रयत्न किया या तथा इस सन्दम म एक योजना प्रस्तावित की थी ।
इसके अन्तगत स्थानीय, बोनीय एव राष्ट्रीय परिषदा के निर्माण का सुभाव दिया गया
था । इसके अतिरिक्त योजना ये एक पच फीसला सिमिति (Arbitration Commit
tee) की स्थापना की भी व्यवस्था थी विवक्त काय दोना पक्षा का सुनन र विवाद के
सम्बन्ध म निषय देना है । राष्ट्रीय सिमिति जब किसी विवाद की निवटाने में असफल
रहती है तो वह विवाद पच-फसला सिमिति को निष्याय अब दिया जाता है । 1963
ई म इस योजना को जासन ने नियाचित वरने की घोषणा इस छत पर की थी कि
धासकीय कमजारी इस्ताल के याय का अनुसरण न करने की घोषणा करे। 1966 ई
म के द्वीम कमजारियां के लिए समुक्त परामश्च एवं अनिवाय वच फैसले की योजना
प्रस्तुत की गयी है।

समीक्षा— आधुनिक वासन प्रणाली य लोक संवका या सरकारी कमजारियों के दायित्व नकारात्मक न रह कर सकारात्मक हो गय है। उह अब केवल व्यवस्था एवं साित की स्थापना में हो योग नहीं देना है। आधुनिक राज्य आधिक, सामाजिक एवं साहित के अनेव का व्यवस्था ने परता है। मुक्त स्थापार नीतिका युग वीरा चुना है। सामाजवादी व्यवस्था की स्थापना का प्रयत्न किया जा रहा है। नियोजन हारा आधिक उनति अधिकाश देशों का आदर्श है। यह सभी दायित्व दासकीय कमचारियों का ही सम्मादित करने पडते हैं। वह सामाजवादी करने पडते हैं। वह सामाजवादी करने पडते हैं। वह सामाजवादी स्वयं रायव्याप में व्यापन परिवतन अपेक्षित है। नीक-सेवका को आज अधिक निरुद्धात्म, सन्ध्या रायाण एवं मीम्य होने की वायरवकता है। अब जनता पर निरुद्धा हम दायान करने का समय बीत चुका हमनवन अपनित है।

विमिन्न देश की लोन-सेवाआ म (1) सरकारी कमवारिया की सख्या म तीव्र बिंद हो रही है, (2) अधिकाधिक सरमा म तक्नीकी याग्यता से गुक्त व्यक्तिया एव विद्येश्वों की शास्त्रीम कमवारी निमुक्त विमा जा रहा है, फनस्वरूप नोक सवा म विमिन्न नवीन सेवार्ए (diversification) विवसित हो रही है, (3) लाक सेवा की शक्ति में नृद्धि हो रही है, (4) परम्परागत तटस्यता की धारणा में भी परिवतन हो रहा है, तथा (5) नैतिक आवरण एव दायित्वा सम्बन्धी मानदण्डा के पालन पर अधिकाधिक वल दिया जा रहा है।

सासन के दाबित्व एवं काय म बृद्धि के साथ सरकारी कमचारिया की सत्या एवं शक्ति में बृद्धि स्वामाविक है। पारिक सन के अनुसार लोक-सेवनों की सह्या में प्रति वप 5 75 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। ब्रिटन म 1797 ई में वेचल 16 हजार कमचारी थे। 1857 ई में उनकी सहया 6,37,423 हो गयी थी। 1817 ई म समुक्त राज्य अमरिका के संध्या कमचारिया की सम्या 6,500 थी, 1957 ई म व

730 | आधुनिक शासनतात्र

23 लाख थे। भारत म 1947 ई एव 1957 ई के मध्य सरकारी कमचारिया नी वद्धिका अनुपात 23% है। इसके अतिरिक्त अब शासकीय कमचारिया में तकनी शियना एव विशेपका की भरमार है, केवल सामा य प्रशासक एव लिपिक ही नियुक्त नहीं किये जाते हैं । लोक सेवा की शक्ति में भी जसाधारण वद्धि हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, भारत एव अय देशों से यह प्रवृत्ति सुम्पष्ट है । रमजे स्योर ने ब्रिटिश लोक सेवा के सदम में यह कहा है कि "नौकरशाही की शक्ति में असाधारण वद्धि हुई है। मन्त्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व के आवरण में नौकरशाही फलती फूलती है एव मि निमण्डल के अधिनायकत्व के अधीन यह निरतर विकसित होती जा रही है।"" नौकरशाही अग्नि की माति है जो सबक के रूप में महत्वपूज है लेकिन स्वामी के रूप मे विनाशकारी है। ⁸ मारत मे यही स्थिति है। मारत में यदि लोकतान असफल होता है तो उसका मुरय दायित्व लोक सवको एव उनकी उत्तरदायित्वहीनता की निरतर बढती प्रवित पर होगा। इसके अतिरिक्त नियोजित अय व्यवस्था द्वारा समाजवादी समाज के निर्माण के लिए कृतसकल्प होने के कारण शासकीय कमचारिया के दायिस्वो म असाधारण विद्व हुई है। आज लोक सेवा का सदस्य अफसर नहीं है, वह जन सेवक है। हमारी योजना की सफलता शासकीय कमचारियों में अफसरशाही, भ्रव्याचार एव अय कमजीरियो के हटने पर ही सम्भव है।

लोक सेवा की विशेषता जनकी निप्पक्षता एव तदस्यता है। इसका अप है कि व राजनीतिक मामला म तदस्य हाते है। ब्रिटिश विचारधारा के अनुसार लोक सेवा के सदस्यों की राजनीतिक तदस्यता का अप है कि लोक-सेवा का राजनीतिक तिपक्षता के सदस्यों की राजनीतिक तदस्यता का अप है कि लोक-सेवा का राजनीतिक निप्पक्षता में विश्वास होना चाहिए, लोक सेवा के सदस्या को प्रत्येक सरकार की पूरी निप्ता से सेवा करनी चाहिए चाहे वह सरकार किसी भी दक को स्था न हो, एव घात कीय कामवारियों को योग्यता के आधार पर तदस्की पढ़ अप यारितोषिक प्राप्त होत रहने चाहिए। सयुवत राज्य अमेरिका न भी तदस्यता को यही धारणा मान्य है अबांत लोक सेवा के सदस्यों को सभी राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए, उन्हें व्यक्तिगत या सावजनिक रूप मा काई वस्त्य्य नहीं देना चाहिए और न दलीय या विवासप्य मामला पर विचार ही ज्यक्त करने चाहिए। लेकिन जाता है कि नीति निर्माण एक व्यापक एव सहयोगी प्रक्रिया है, न कि किसी मंत्री या कमवारी का कोई यत्त्वनत काय। अत लोक-सेवा ने सदस्यों का काम केवल नीति को प्रियांचित करना ही नहीं है। लोक सेवको नो दत्यतर राजनीति से दूर रहना चाहिए पर जुगासकीय नीति को प्रयांचित करना ही नहीं ति को प्रियांचित करना ही नहीं है। लोक सेवको नो दत्यतर राजनीति से दूर रहना चाहिए पर जुगासकीय नीति को प्रयांचित करना ही नहीं ति को स्वांचित करना सेवल नीति को स्वांचित करना ही नहीं सेवलिय काय। अत लोक-सेवा ने सदस्यों का सम्बंदि से दूर रहना चाहिए पर जुगासकीय नीति को प्रयांचित करना सेवलियों काय केवल नीति को स्वांचित करना साहिए।

⁷ Ramsay Muir op cut, Ch II, pp 51 60

⁵⁸ Ibid p 53

लेकिन लावत य म लोक सेवा लोकप्रिय शासन का अभिन्न अग होती है। लोक सेवा के काय नकारात्मक न होकर अब सकारात्मक हो वये हैं। सफलतापूर्वक किसी तीति के काय नकारात्मक न होकर अब सकारात्मक हो वये हैं। सफलतापूर्वक किसी तीति को प्रियाचित करने के लिए उस गीति मे पूर्ण निष्ठा भी वाद्याय है। अत कहा जाता है कि लोकसेवा को राजनीतिक होट से तटस्य नहीं होना चाहिए। समर्पत लोक सवा (Committed Services) की चर्चा अब भारत म भी मुनी जाती है। तरस्य लोक (Committed Services) की चर्चा अब भारत म भी सुनी जाती है। तरस्य लोक सेवा के विच्छ यह तक दिया जा रहा है कि समाजवादी ख्यस्या के निर्माण म वह पूपत असकत रहेगी बयोकि समाजवादी आवशी के साथ उसका वोई रागात्मक पूपत असकत रहेगी बयोकि समाजवादी आवशी के साथ उसका वोई रागात्मक समाजवादी आवशी है।

25

न्यायपालिका [JUDICIARY 1

'यदि विधि का प्रशासन वेईमानीपूवक किया जाता है तो उसका वाधित प्रभाव नहीं होता और यदि शिम्बलतापूवक या आवेश में विधि को क्रियाचित दिया जाता है तो व्यवस्था सम्बंधी प्राप्त प्रतिभू समाप्त हो जाती है नयाकि अपराधों को दण्ड की कठोरता की अपेक्षा उसकी निश्चितता से ही रोका जासकता है। यदि अप्य-कार म याय का दीप बुक्त जाता है तो वह अधकार भयानक होता है। '

आधुनिक राज्यों से यायपालिका की स्वतंत्रता पर बहुत बल दिया गया है। लोक्त न में यायपालिका की स्वतंत्रता का विश्रंप मह्त्व है। व्यक्ति के स्वतंत्रता एवं समानता के आधारभूत अधिकारों की रक्षा के लिए यायपालिका आधुनिक समाज की अनिवाय आवश्यकता है। यायपालिका निरकुद्य शासन से व्यक्तियों की रक्षा की अनिवाय आतं की साना जाता है। यह समय शासन-व्यवस्था की एक अनिवाय शत है। लाझ बाइस के अनुसार, "किंक्षी भी देश की श्रंप्ठता का सापदण्ड उस देश में अपेट यायपालिका होती है।" वाँ आशोर्वाव्य का क्यन है कि किसी देश में अच्छी ध्यवस्थापिका एवं कुशंव कायपालिका मले ही हो पर तु स्वतंत्र प्रविच्या स्थान पालिया के अमाय मं उस देश के श्रंप्यान का विश्वंप महत्व नहीं है। विषय स्थान पालिया के अमाय मं उस देश के श्रंप्यान का विश्वंप महत्व नहीं है। विषय स्थान

^{1 &#}x27;If the law be dishonestly administered the salt has lost its flavour if it be weakly or fitfully enforced, the guarantees of order fail for it is more by the certainty than by the severity of punishment that offences are repressed. If the lamp of justice goes out in darkness how great is that darkness '-Lord Bryce Modern Democrates, Vol. II, 1929, p. 421.
2 Lord Bryce Ibid.

Dr E Asırvatham Political Theory, 8th edn . p 428

न्यायपालिका का विकास

यायपालिका का विकास अत्यात धीमी गति से हुआ है। आधुनिक राज्या म 'याय का सम्पादन सावभीम रूप सं 'यायपालिका का एकाधिकार है। परात ऐसा सदैव नहीं था। आदिकाल में यात्र राज्य का दायित्व न होकर व्यक्ति का निजी दायित्व था। इसके अतिरिक्त उस समय यह आवश्यक नही था कि अपराधी को ही दण्ड दिया जाये। अपराधी के कबीले या गोत्र के किसी अय व्यक्ति की दण्ड या हानि पहुँचाकर भी 'याय की पूर्ति हो सकती थी। उस समय 'आँख के बदले आंख' और 'खुन के बदले खुन' का सिद्धात प्रचलित था। घीरे धीरे आर्थिक क्षतिपूर्ति का प्रच-लन प्रारम्म हुआ । पर तु क्षतिपूर्ति (Wergild) के लिए कोई प्रशासकीय व्यवस्था नहीं भी तथा दण्ड एव अपराध मं भी कोई अनुपात नहीं था। समाज से वहिष्कृत करने के कठोर दण्ड का प्रचलन था। धीरे और राजा द्वारा याय (Kings peace) की धारणा का विकास हुआ था। प्रारम्भ म राजा केवल उही विवादा में निगय देता था जिनमे क्षतिपूर्ति किया जाना असम्मव था, बाद मे चोरी एव अप अपराधी के लिए भी राजा याय करन लगा। पाइचात्य समाज मे साम तो एव चर्चों द्वारा एक लम्बे समय तक 'याय सम्पादित किया गया था । भारतवय म ब्रिटिश शासन काल के प्रारम्म तक पचायते याय करती थी। आधनिक समाज म याय राज्य का एका धिकार है और याय सम्पादित करना राज्य का एक महत्वपूण काय है। आधिनिक समय मे सभी अपराध राज्य के विरुद्ध माने जात हैं। मले ही विभिन्न सस्थाओं या सामाजिक संगठनो द्वारा व्यक्ति पर नैतिक दबाव एवं सामाजिक प्रतिब व लगाये जाते हो पर त व्यक्तियो को अपराधो के लिए कारावास. मत्यु दण्ड जसे दण्ड देने का अधिकार केवल राज्य को ही है।

कतन्यो एव दायित्व के जाबार पर यायपालिका की दो महत्वपूण विद्योपताएँ है (1) स्वत नता, एव (2) निष्यक्षता। ये दोना यायपालिका के सगठन, त्याया भीवों की योग्यता एवं उनकी क्षेत्रा क्षम्य धी शर्तों पर निषर करती है। त्यायपालिका के काय एवं दायित्वों की हिस्ट के त्यायपालिका की स्वतानता एक अनिवाय सामा- विक्र आवय्यकता है।

न्यायपालिका के कार्य

आधुनिक राज्या में यामपालिका का प्रमुख काथ याय का सम्पादन है, लेकिन उसके द्वारा अय काय या वायित्व भी सम्पादित किये जाते हैं। उसके दायित्वा को पायिक एवं अप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यायिक दायित्व निम्मवत हैं

- (1) व्यक्ति एव व्यक्ति तथा व्यक्ति एव राज्य के मध्य उत्पन्त समस्त दीवानी एव फोजदारी विवादों में निषय देना एव अपराधियों को दिष्डन करना, तथा निर्दोप व्यक्तियों की हिंसा, हानि एव अपहरण से रक्षा करना।
 - (2) किसी विवाद में विधि के अस्पष्ट होने पर उसकी व्याल्या करना। इस

प्रकार की विधि को Case law या यायाधीय द्वारा निर्मित विधि कहत है इनलेण्ड की सामा य विधि—कॉमन लॉ— यायाधीयों के निणयों पर ही आधारि विधि है। विदिश्त विधि यवस्था वाले देशों में विधि के अमान या अस्पटता की दर म यायावयों द्वारा दिये गये निणय नजीरों (Precedents) का रूप धारण कर लें हैं। फ़ास व जमनी बादि देशों में यह नजीरे सामा य यायावयों पर व धनकारी गई होती है। यायपानिका ही सविधान की व्याख्या करती है एव सविधान तथा मौतिक अधिकारों की सरक्षक होती है। सविधान विरोधी विधि को यायालय अवैधानिक घोषित करते हैं।

(3) कमी कभी यायालया के समझ ऐसे विवाद आते हैं जिनके सम्बाध मे विधि मीन होती है। ऐसी अवस्था मे यायाधीश सामान्य विवेक, नतिकता के सामान्य सिद्धानों तथा सामाजिक न्याय के आधार पर उचितानुचित का निणय करते हैं। फ्रांस की सम्पूण प्रशासकीय विधि देश के सर्वोच्च प्रशासकीय न्यायालय—राज्य परिषद (Council of State)—के द्वारा दिये गये न्यायिक निणयों का ही सम्रह है।

(4) राज्य के हुस्तक्षिय या अतित्रमण से व्यक्ति की रक्षा करना यायपानिका का महत्वपूण दायित्व है। सधुक्त राज्य अमेरिका एव भारतीय सर्वाच्य यायावय की मौलिक अधिकारो का सरक्षक कहा जाता है।

(5) सधीय राज्या म यायपालिका एकास्मक राज्यो की अपेक्षा अपिक महत्वपूण भूमिका निमाधी है। सधीय राज्य मे यायपालिका केन्द्र व राज्य, राज्य व राज्य तथा केन्द्रीय या अय्य राज्य/राज्या, व्यक्ति या व्यक्तियो के मध्य उत्पन विवादों के सम्बन्ध में निणय करती है। सिवधान सम्बन्धी विवादों म यायपालिका द्वारा सविधान की व्यारया की जाती है तथा शासन के विधिन अया के क्षेत्राधिकार सम्बन्धी

विवादों में निणय देती है।

"यायपालिका के 'क्ष य कार्यों' को दो वर्गों म विमाजित कर सक्ते ह-(1) राजनीतिक, एव (2) कायपालक।

(6) राजनीतिक वायित्व के अत्यात व्यवस्थायिका द्वारा निर्मित विधियो एव कायपालिका के कार्यों की वधानिकता के सम्बध म निषय करने का अधिकार "याजपालिका को प्राप्त है। इसे सायिक पुनरींत्रण या यायिक समीक्षा (Judicial review) को सिक्त कहत हैं। समुक्त राज्य अभिक्ता क सर्वोच्च यायात्य को स्थापित पुनरींत्रण की व्यापक शक्ति प्राप्त है। भारत के सर्वोच्च न्यायात्य को सिंध पान की सीमा के अत्यात ही यह श्राफ्त प्राप्त है पर तु ब्रिटिश यायात्या वो यायिक पुनरींत्रण सम्बधी वाक्ति विक्ति मही है।

(7) यामपालिका क जनक छोट मोट कायपालक दायित्वा को सम्पादित

करन ना अधिनार है। जस—

(अ) 'यायालय विभिन्न प्रकार की निषयाताएँ (Writs) जारी कर सकते हैं।

(आ) किसी सामले स सम्बंधित पन्ता क आग्रह पर घोपणात्मक निणय (declaratory judgments) व सकते हैं।

(इ) कायपालिका या व्यवस्थापिका द्वारा प्राथना करन पर किसी विषय पर

परामशदायी मत व्यक्त करने का अधिकार है।

(ई) अनक प्रकार की व्यक्तिगत एक सावजीतक सम्पत्ति तथा ट्रस्टा के प्रवाध का मार बहन कर सकत हैं।

(उ) यामालयो क अनक छोट माटे कमचारिया का नियुक्ति करने, नाइस स देने, अल्पसस्यको क सरक्षका को नियुक्त करने, वसीयसे स्वीकरने एव नि सत्तान मृत स्पक्तियों की सम्पत्ति की देखभान के अधिकार प्राप्त हैं। यायपानिका के उप-रोक्त दो कार्यों पर अग्रिय पृष्ठा म विस्तार से विचार किया गया है।

 राज्य के अतिश्रमण से स्पवित की रक्षा करना---राज्य के जनचित एवं अवधानिक वार्यों सं व्यक्ति की रक्षा के सम्बाध में एक प्रचलित धारणा यह है कि सविधान म अधिकारी की व्यवस्था के माध्यम स ही व्यक्ति की रक्षा सम्मव है। मयुक्त राज्य अमेरिका एव भारत के सर्विधानों म नागरिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। दोना ही देशा म न्यायपालिका सविधान एव मौलिक अधिकारा की सरक्षक है। अमेरिकी यायपालिया को इस सम्ब ध में यायिक पूनरीक्षण की व्यापक शक्तिमा प्राप्त है। इसका आधार अमेरिकी सविधान स प्रयुक्त 'विधि की उचित प्रतिया' (due process of law) नाक्यास का प्रयोग है। इस वाक्यास का अब बाहबत विवेशाधित याय के मुलभूत सिद्धा तहै। भारत के सर्वोच्च यायालय को इतने व्यापक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। मारतीय सर्विधान में विभि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure established by law) वाक्याश का प्रयोग किया गया है। स्मरणीय है कि भारतीय सर्वोच्च यायालय ने दो आधारा पर यायिक पूनरीक्षण की शक्ति र्जीजत की है—(1) मविधान की माया, एव (2) मौलिक अधिकारा पर उचित प्रतिव प (reasonable restriction) की व्याख्या करक । भारतीय उच्च यापालया एवं सर्वोच्च "यायासय न मीलिक अधिकारी पर शासन द्वारा लगाये गय प्रतिव धा क औचित्य के सम्ब ध में निर्धारण को "यायानय का अधिकार माना है, फलस्वरूप भार-तीय न्यायपालिका को त्यायिक पूनरीक्षण के व्यापक अधिकार प्राप्त हो गये हैं।

सोवियत रूस के सविधान में भी मौतिक विधकारा का उल्लेख है, पर तु

वहा यायपालिका की यायिक पुनरीक्षण की नोई शक्ति प्राप्त नही है।

ब्रिटेन, कमाडा आदि देशों म मौलिक अधिकारों का मविधान में उस्लेख नहीं किया गया है। ब्रिटिश सविधान अतिश्वित एवं विकासका परिणाम है। मते ही ब्रिटिश सविधान में समुक्त राज्य अमेरिका एवं मारतीय सविधान की मौति भौतिक

⁴ मौतिक अधिकारा की विस्तृत व्याख्या के लिए देखिए जध्याय 33

अधिकारा का उत्तेव नहीं है परन्तु व्यक्ति की स्वतन्त्रता ब्रिटन मे अधिक अञ्चाहै। 'त्रिटन म विधि का सासन है व्यक्ति का नहीं।' स्वय ब्रिटिस सविधान हो व्यक्ति को स्वतन्त्रता का परिधाम है। मौतिक अधिकारा की आवस्यकता एव रक्षा के प्रमत्ता का ही परिधाम त्रिटिस सविधान है। त्रिटन म सपद सम्प्रमु है और वहां के न्याया लया को क्लिसी सवदीय विधि को अवैधानिक घोषित करने का अधिकार नहीं है। वह विधि को उसको नाथा के आधार पर केवल व्याख्या करन की शक्ति है, परन्तु विटिस प्राप्ताय त्रिटिस प्रजाजना क अधिकारों की रक्षा के लिए इत्त-क्रव्य हैं। मिकत वेन (Macliwam) के अनुमार ''इगलैण्ड म विचित्त सवधानिक अधिकारा की आव स्वकता नहीं है वयाकि वहा विधि के द्यासन' (Rule of Law) सी परम्परा अिंत प्राचीन है।

स्वित सविधान म भी लिखित अधिकार-पत्र नहीं है परन्तु सविधान म अनेक ऐसे अनुष्ठेद हैं जो नागरिका को अनेक स्वत नताएँ प्रदान करते हैं। स्वित सपीय न्यायात्य का सपीय व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधियों को अवैधानिक घोषित करने का अधिकार नहीं है और न उस सप्यंपालिका के किसी कार्य को ही अवधानिक घोषित करन का अधिकार है। लेकिन सपीय न्यायाल्य कैस्टना की विधियों को सपीय सिंव धान के विच्छ होन पर अवैधानिक घोषित कर मकता है।

फान्स, जमनी, इटली एवं जाय महाद्वीपीय देशों ने प्रशासनीय विधि एवं प्रशासनीय याय व्यवस्था प्रचलित है। अत दन देशों ने बादकीय कमचारिया सम्बंधि पृथक विधि न्यायालय हैं जो मामा य जनता स सम्बंधिन विशि एवं न्यायालयों स पृथक हात हैं।

(2) सपीय शासन-व्यवस्था से यायवासिका के दावित्व—स्वीय पासन व्यवस्था क ज तमत यायवासिका सिर्धान की सरक्षक होती है। सपुक्त राज्य अन-रिका एव नारत के सर्वोच्च यायालयों को सपीय शासन तथा राज्यों के शासन के क्षेत्राधिकार सम्बची विवादा म मीसिक क्षेत्राधिकार प्रान्त हैं अपात् सपीय स्वीय-यायालय क्षत्र एवं राज्यों में उनक सैत्राधिकार सम्बची विवादा के सम्बच्च म निष्पक्ष एवं स्वतात्र निणायक क द्यायिकार करता है। स्विट्यत्तक अ सिंद्यान में प्रमास्था का अधिकार स्वित्त स्वायान्य (federal Inbunal) को प्रान्त नहीं हैं अपितु सपीय सना (Federal Assembly) को प्राप्त हैं।

न्यायपालिका का सगठन

सभी दशा म 'याय व्यवस्था का सगठन एक समान नही है। हर दंग म अपने अनुमन एव परम्पराक्षा तथा राजनातिक सिद्धा तो न' अनुसार उनका विकास हुआ है। पिर भी इस मध्याथ में विभिन्न दंगा में अनक वातो में माइदय मिलता है। हर दंग म 'यायासवा का सगठन एक भूगला के रूप म होता है। सबस दीय पर सर्वोत्त्व यामालय और सबसे नीचे छोटे छोट "यायालय होते हैं। इन छोटे यायालयो के ऊपर उनस बडे "यायालय होते हैं और छोटे "यायालयों को अपेक्षा कुछ अधिक गम्मीर मुक्दमा क निणय का अधिकार प्राप्त होता है। उच्चतम "यायालय विशेष विवादा का निणय करते है एवं नीचे के "यायालया के निणयों के विरुद्ध उनके द्वारा अपीला की मी मुनवाई होती है।

ब्रिटिस यायिक व्यवस्था से प्रमानित देखों भ अपीली यायालयों को छोडकर अय प्रश्यक यायालय म सामान्यत एक यायाधीश होता है, पर तु फ़ा त, जमनी एव अय पूरोपीय देखों म नीचे को अदालतों म अनेक यायाधीश होते हैं एव एक साय मुन्दमें की मुनवाई करते हैं। यह व्यवस्था अस्य त खर्चीली होती हैं पयापि कई यायाधीशा की उपस्थित के कारण वाह्य दवाब का भय कुछ कम हो जाता है एव यायाधीशा के लिए मनमानी करने के भी अवसर नहीं पहुते हैं। नीचे की अदालतों म जिटेन एव समुक्त राज्य अमेरिका म अपेक्षाकृत यायाधीशों की सक्या कम होती है।

सामा यत दीवानी एव फीजदारी यायालय पृथक तृथक होते है। गानर दो प्रकार के यायालयो—सामा य एव विश्रेष—का उल्लेख करते हैं। विशेष प्रकार के यायालय के अन्तगत सिनक यायालय, औद्योगिक यायालय, अम यायालय, महामियोग यायालय, सामिक यायालय आदि आते हैं। इनम से अधिकाश यायालय केवल ऐक्षिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं। का स के प्रधासकीय यायालय मी विशेष प्रकार के यायालय की विशेष है। का स के प्रधासकीय यायालय मी विशेष प्रकार के यायालय की श्रेषो म ही आते हैं। इनकी प्रक्रिया एव सम्बधित विशेष विशेष प्रकार की होती है।

त्रिटेन एव गूरोप महाद्वीप के अन्य देशों की याय व्यवस्था में आधारभूत अत्तर हैं। अमेरिका एव ब्रिटिश प्रणाली म यायाधीश प्राय दौरा करत हैं अर्थीत विमिन्न स्थाना में वे णाकर मुकदेश सुत्रते हैं, पर तु युरोप के देशा म यायालय एक ही। स्थान पर स्थित होते हैं और सम्बर्धित पद्मा को वही जाना पडता है। अमेरिकी एवं स्थाना पर स्थित होते हैं और सम्बर्धित पत्म को वही जाना पडता है। अमेरिकी एवं स्थानात की स्थवस्था एकि हैं, अविक समुक्त राज्य अमेरिका में दौहरी याय व्यवस्था अर्थीत राज्यों एव सब की पृथक पथक याय व्यवस्था होती हैं। अमेरिका की दौहरी याय व्यवस्था को सभी सधीय देशों ने स्थीकार नहीं किया है। उदाहरण के लिए जमनी के बीमर संविधान के अत्यत्त सध एव राज्यों की न्याय व्यवस्था एकिहत थी। मारतीय गराज्यों को नाय व्यवस्था पिकार सी। मारतीय गराज्यों के याय व्यवस्था में स्थित होते हैं। समुक्त पत्म से सप एव राज्यों के सामालायों के क्षेत्राधिकार नमग्न संवीय कानूना एवं विषयों तथा राज्यों के कानूनों गय विषया तक सीमित होते हैं, पर तु मारत में ऐसा नहीं है। मारतीय याय-व्यवस्था के यायालया को के द्व एवं राज्य दोनों ही विधियों एवं विषयों म क्षेत्राधिकार प्राप्त है। विधियों एवं विषयों म क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

न्यायाघीशो को नियुक्ति

न्यायाधीया की निवृक्ति की तीन प्रधान पद्धतिया प्रचलित हैं—(1) व्यवस्या पिका द्वारा निर्वाचन, (2) जनता द्वारा निवाचन, एव (3) कावपालिका द्वारा नियक्ति।

- (1) व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन—संगुक्त राज्य अमेरिका के राज्या म यह प्रचाली प्रचित्त थी और चार राज्यों म आब भी इसका प्रचतन है। त्विट्यरतम्ब्र के सीथा यायासय के 24 न्यायाधीश्चा को त्त्विस व्यवस्थापिका के दोनो सहना द्वारा 6 वप के सिए संगुक्त अधिवेशन म निर्वाचित क्या जाता है। यह पद्धित शेष्ट्रम है। व्यवस्थापिका के संस्था से याविष यह आशा की जाती है कि वे यो य एवं ईमानशा व्यक्तियों को ही यायाधीश के रूप में चुने पर तु प्राय ऐसा सम्मव नहीं है। सरव ही बहुमत दल के सदस्य चुने जाते हैं। योयाधीश के रूप में चुने पर तु प्राय प्रमान के सबयों मा चुना जाना प्राय असन्भव होता है और ऐसे न्यायाधीशों के लिए दलीय प्रमान से सबया मुक्त होना सम्मव नहीं होता है। ससदीय प्रमानों में कायपालिका स्वस्थापिका को तेतल करती है अत व्यवहार म इस पहलि के अनुसार व्यवस्थापिका स्वाय यायाधीश के स्वपन का अस्य मायपालिका द्वारा उनकी नियुक्ति है। त्विट्यराज्य म सम प्रमानिका हारा उनकी नियुक्ति है। त्विट्यराज्य म सह पदिस समय व्यवस्थापिका के सदस्यों की सम्या कम है तथा विद्युक्त रूप राजनीतिक दक्तीय व्यवस्थापिका के सदस्यों की सम्या कम है तथा विद्युक्त रूप राजनीतिक दक्तीय व्यवस्थापिका होरी नहीं है।
- (2) जनता द्वारा निर्वाचन- संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्या एवं कुछ स्विस कैंग्टना म बाज बी इसका प्रचलन है। फान्स की बान्ति के द्वारा सोक प्रमुख के सिद्धात का प्रचार हुआ था। फ्लस्वरूप जनता द्वारा निर्वाचित न्यायाधीको का सम यन किया गया। फ्रांस म भी इस पढिति का कुछ समय तक प्रवतन रहा था। सहिन 1793 ई म इसका बहुत दुरप्योग हुवा था, शभररास, लिपिक, माली एव सामाय प्रमिक यायाभीश निवाचित हुए थे। नैपोलियन ने इस पड़ित को समाप्त कर दिया । स्थिटजरलैण्ड म छोटी अदालतो के न्यायाधीश जनता द्वारा ही निवाचित होते हैं। यह पढ़ित निश्चम ही विशुद्ध लोक्त नीय पढ़ित है परन्तु झदहार म इसम अनेक दोप हैं—(1) जनता सामा यत विधि विरोपण एवं चरित्रवान न्याया भी भा का वयन करन म असफल रहती है। (2) प्राय जो प्रत्यासी जनता को बह कान म असपल हो जाते हैं व हो निर्वाचना म चुन लिय जात हैं। (3) जनता केवत योग्यता ॥ प्रमावित नही होतो । निर्वाचन म जीतन ने लिए यायाघीरा को समी प्रकार क ह्ययण्डा का प्रयोग करना पढता है अत निर्वाचित होने के पश्चात उनस पूण इमानदारी को आधा नहीं को जा सकती। संयुक्त राज्य अमेरिका म सांगाधीया क चयन व' लिए निदलीय समितियाँ नियुक्ति की गयी हैं। उनके द्वारा योग्य प्रत्या िया न नाम ही यायाधीया क पदा क लिए प्रस्ताबित बिच जात हैं। इस ध्यवस्था म इस पद्धति व दोषा पर कुछ प्रतिबाध लग गया है। आँग एव रेका क्यत है कि

38 राज्यों में से, जिनमें यह प्रणाली प्रचलित है, केवल 3 राज्यों म ही यह प्रणाली कुछ स तीषप्रद रही है। पिलकाइस्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका म अनंक ऐसे उदाहरण है कि निर्वाचनों में योग्य प्रत्याची हार गये हैं। जहाँ यायाधीशों का कामकाल अरूप होता है तथा यायाधीश पुन निर्वाचन हो सकते है, वहा अनता द्वारा निर्वाचन की पद्धति के परिणाम और भी बुरे होते हैं। ऐसी स्थित में यायाधीश से निर्वाचन की पद्धति के परिणाम और भी बुरे होते हैं। ऐसी स्थित में यायाधीश से निरुक्त की अन्ना नहीं की जा सकती 15

(3) कायपासिका द्वारा नियुक्ति—अधिकाश देशो मे 'यायाधीशो को काय-पालिका द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह पद्धति उपरोक्त दोनो पद्धतियो की तुलना मे अधिक श्रेष्ठ है। पर तु इसे भी हम निर्दाप नहीं कह सकते । कायपालिका द्वारा सदैव ही योग्य एव अनुमवी व्यक्तिया की निष्पक्षतापूर्वक नियुक्ति नहीं की जाती है और न कायपालिका दलगत भावना से ऊपर उठकर ही सदैव आचरण करती है। एक बार नियुक्त हो जाने पर यायाधीश पर्याप्त स्वत त्रतापूवक कायपालिका के प्रमाव सं मुक्त होकर काम करते हैं। जीवनपय त या सदाचरण पय त नियुक्ति की व्यवस्था कार्यपालिका द्वारा नियुक्त यायाधीशो को एक बड़ी सीमा तक स्वत त्रता प्रदान करती है। ब्रिटेन, राष्ट्रमण्डलीय देशो तथा उपनिवेशो, सयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया एव उसके 6 घटक राज्या एव भारत म यायाधीशों को कायपालिका द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। मारत म छोटी अदालतो के यायाधीशो की प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से नियुक्ति की जाती है। फास मे भी निस्न अदालती के यायाधीरा इसी रीति से नियुक्त किये जाते हैं। भारत एव फास में निम्न या छोटी अदालता क पायाधीशों की वरिष्टता के आधार पर पदो नित होती रहती है। फान्स म सर्वोच्च चायालय के यायाधीको की नियुक्ति यायम त्री द्वारा की जाती है। फेंच व्यवस्था-पिका के सदस्य 'यायम' नी को प्रमावित करने का प्रयत्न करते हैं। अत यह मुम्प्रव दिया गया है कि उच्च "यायालय द्वारा प्रस्तावित नामावली म स ही कायपानिका द्वारा यायाधीशा का चयन किया जाना चाहिए।

यायाधीकों की नियुक्ति के सम्बाध म कुछ सुभाव दिव गय हैं। लॉस्ती का क्यन या कि "वायाधीकों की नियुक्ति यायम त्री को यायाधीका त्री एक स्थावी समिति (जिसम यायिक कार्यों का प्रतिनिधित्व करन वाल यायाचाद्र द्वा) त्री नित्म रिरा पर ही करनी चाहिए नयांकि वकीता क बार म जितना व बतात है उतना मान बहुत ही कम सोगा को होता है तथा उनक सबनीतिन प्रतिष्ठा स प्रमावित होन त्री भी आसा नहीं है।" मारतीय सविधान निमाता सम्मवत लास्की न इस विचार के

⁵ Ogg & Ray Introduction to American Government, 8th edn F Gilchrist Principles of Polytical Science, 1930 p 316

⁷ Laski Grammer of Pelities, 1941, p 548

आशिक रूप से प्रमावित हुए थे। मारतीय सविधान मे यह व्यवस्था की गयी है कि मारतीय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के यायाघीशो की नियुक्ति करते समय सर्वोच्च न्यायाधीश से परामश करेगा तथा उच्च यायालय के यायाधीशो की नियुक्ति में उच्च "यायालय के मुख्य "यायाधीश एव सर्वोच्च "यायालय के प्रधान "यायाधीश से परामग्र करेगा । इन व्यवस्थाओ द्वारा न्यायाधीशो की नियुक्तियो के सम्बाध म कायपातिका की निरकुशता पर प्रतिब घ लग जाता है।

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता

न्यायपालिका की श्रेष्ठता उसकी स्वत त्रता, निप्पक्षता एव दक्षता पर निगर करती है और यायिक निष्पक्षता तथा दक्षता यायपालिका की स्वत नता पर निमर होती है। स्वतात्र एव निष्पक्ष यायपालिका के अभाव मे शासन पूगरूपेण निरकुरा होता है तथा सविधान एव मौलिक अधिकारो का सरक्षण मी न्यायपालिका की स्वत नता के अमाव मे असम्भव ही है। यायपासिका की स्वत नता का अय यह है कि यायाधीश मय एव आतक रहित होकर आचरण करे तथा अपने दायित्व के सम्पा दन म किसी व्यक्ति अथवा सस्या से प्रमावित न हो । अंत यह आवश्यक है कि 'यायाधीशो की निष्पक्षतापूरक नियुक्ति की जानी चाहिए, उनका कायकाल निश्चित होना चाहिए तथा उनको समुचित बेतन प्रदान किया जाना चाहिए जिससे कि वे आर्थिक दुविच ताओं से मुक्त रहकर अपने दायित्व का सम्मादन कर सके। इसके वित रिक्त "यायपालिका की स्वतन्त्रता के लिए निम्न वार्ते भी आवश्यक हैं

(1) याय के कुछ निद्दिचत सिद्धान्त होने चाहिए जिनका पालन पूण ईमान

दारी स किया जाना चाहिए,

(2) यायिक कायपद्धति के नियम होने चाहिए, तथा

(3) यायालया एव वकीलो का अपना नैतिक स्तर होना चाहिए।

याय के कुछ प्रमुख निश्चित सिद्धात निम्नवत् हैं (1) खुली अदालत में ही मुकदमा चलाया जाना चाहिए, (2) अपने से सम्बन्धित पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए वकीला को नियुक्त करने की स्वत बता होनी चाहिए, (3) प्रमाण का वायित्व लारोप लगाने वाले पदा पर होना चाहिए, (4) जूरी व्यवस्था भी होनी चाहिए, एवं

(5) प्रमाण के आधार पर ही दण्ड दिया जाना चाहिए।

यायालयो की कायपद्धति ऐसी होनी चाहिए कि याय दी घ्रतापूरक सम्पा दित किया जा सके एव कोई विसम्ब न हो। याम म विसम्ब का अय पाप की हत्या है। अत यह आवस्यक है कि सभी विवादों को निपटाने के लिए पर्याप्त यापासर एय न्यायापीश होने चाहिए जिसस कि उनके अभाव म कोई विलम्ब न हो । न्याय व्यवस्या महुँगी भी नही होनी चाहिए। विधियो एव यायिक व्यवस्या म अनेक कमियां हुआ करती हैं जिनका लाम उठाकर प्राय वकील एव सम्बंधित परा मुस्दमां ना निगय होने में विलम्ब उत्पन्न करत रहते हैं। विधि एव विधि स्ववस्था ने इन दोषा को समाप्त करना चाहिए। यामिक पद्धति सीधी, सरल एव कम सर्चीली होनी चाहिए तथा यामिक भूलो के सुधार के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए। अत विवादो के फैसलो के विषद्ध आहत पक्षो को ऊँची अवालता से अपील या पुनरावेदन की पर्याप्त सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए।

कायपालिका को किसी भी अवस्था म यायपालिका को प्रभावित ररने के अवसर नहीं होने चाहिए। यायाधीशो को विधि म पारगत एव निर्भीक होना चाहिए। इसके अतिरिक्त क्कील समुदाय का भी उच्च नैतिक स्तर यायालया की स्वतंत्रता एवं तिष्पक्षता के लिए आवश्यक है।

सभी सर्वधानिक राज्यों से शक्ति पथक्करण के सिद्धात की यायपालिका के सादभ म पण मा यता दी गयी है। स्टांग के अनुसार, "सर्विधानवाद का यह सुनि-विवत सिद्धात है कि यायपालिका को अपने विभागीय नियं त्रण के सादभ में स्वता त होता चाहिए यद्यपि यह प्रश्त (स्वामाविक) है कि उस विमाग के नियानण की सीमा स्या होती चाहिए ?" प्राय समी सबैधानिक सविधानी में यावाधीशा की स्वत नता की समुचित व्यवस्था है। कायपालिका द्वारा "यायाधीशा की अपनी इच्छानुसार पद च्यत नहीं किया जा सनता और न कायवाल के दौरान में उनका बेतन ही कम निया जा सकता है। ग्रेट विटेन में 'यायाधीका को ससद के दोनो सदना द्वारा उनके विद्व प्रतिवदन प्रस्तत करने पर ही काउन द्वारा पदच्यत किया जा सकता है। सयक्त राज्य अमरिका मे संघीय 'यायपालिका के 'यायाधीको की नियक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट के अनुमोदन से की जाती है। लेकिन दराचार या गम्मीर अपराध के लिए प्रतिनिधि को यायाधीशा पर महाभियोग लगाने का अधिकार है जिसकी जाच सीनेट द्वारा की जाती है और उसके स्वीकृत होन पर ही सबीय 'यायाधीशो की पद-च्युत किया जा सकता है। भारत म सर्वोच्च एव उच्च यायालयो के यायाधीशा को अपने नायकाल ने मध्य म पद से ससद के दोना सदना द्वारा 2/3 बहुमत से पुथक-पथक रूप मे दुव्यवहार एव अयोध्यता विषयक प्रस्ताव गारित करने एव राष्ट्र पति को प्रस्तत करने पर ही पदच्यत किया जा सकता है।10 मारतीय सविधान के अनुसार किसी भी यायाधीश का बतन तथा उसके मत्ते उसके कायकाल म, नियक्ति के परचात, इस प्रकार परिवर्तित नहीं किये जा सकते कि यायाधीश को कीई हानि हो। 11 आधिक सरक्षा सम्बन्धी उपरोक्त उल्लिखित आखासन चायिक निप्यक्षता की

^{8 &}quot;It remains one of the maxims of constitutionalism that judiciary ought to be free from control in its own department, though the question arises what are the limits of that department — Strong ob at 1, p 277

Ogg & Ray Essentials of American Government, 1964, p 300

¹⁰ Articles 124 (4) and 217 (1) (b)

¹¹ Article 125

गानर ने कुछ अमेरिकी राज्यों में जनता की माग पर यायाधीशा के प्रता वतन (Recall) की व्यवस्था को निकटभूत में स्वीकृत किये जाने का उस्लेख किया है। अरिजीना, केलिकीमिया, कोलारेडो, केनसास, नेविदा, उत्तरी डेकोटा एवं सौरि गिन नामक सात राज्यों ने अपने सिक्याना म सक्षीयन करके इह व्यवस्था का स्वीकार किया है। सेकिन अधिकादा अमेरिकी विधियादिन्यों ने इस व्यवस्था का यह कह कर विरोध किया कि इसते "यायपालिका की स्वत्य नाता एवं सम्मान को पक्त सम्मा अतएव इस व्यवस्था के स्वीकार किये जान की कम ही सम्मावना है।"

यायिक निष्यक्षता की हिन्द से यह भी आवश्यक है कि यायाधीया को अपने पदावकाश के परचात किसी भी राजकीय पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जयपा अपने कायकाल में वह पूण निष्यक्षता एव निर्माकता से काय नहीं कर सकेंगे। मार

^{12 &#}x27;To give the judges the courage and firmness to do their duty fearlessly they ought to be confident of the security of their salaries and station — Kent, quoted by A Appadoras Substance of Politics 1967, no 77-78

The means of securing an independent judiciary he "in the provision that judges shall be selected without regard to their political affiliations and that once selected they shall hold office, for a long term, for life or during good behaviour, that they shall not be subject to dismissal by executive may be semoved only for misconduct as established by a formal process of impeachment address on the part of both the houses of Legislature and that their compensation shall not be withheld or dimunished during their term of office —Willoughby Government of Modern States, 1936 p. 434

¹⁴ Garner Political Science and Government 1951 (Indian edn.),

तीय सविधान म यह व्यवस्था है कि सर्वोच्च यायालय म यायाधीश ने पद पर रह चकन के पदचात कोई भी व्यक्ति भारत म किसी भी यायालय मे या किसी अधिकारी के समक्ष पैरवी या काय नहीं बरेगा। 15 इस अनुच्छेद से केवल यह प्रतिब घ है कि पदावकाश क पश्चात कोई यायाधीश किसी अदालत म वकालत या पैरवी नहीं कर सकता । स्मरणीय है कि यायाधीश भी राजनीतिक महत्वाकाक्षा से सवधा मुक्त नहीं होते हैं। अनक राजनीतिज्ञ यायाधीश बनत हैं। वे भी सत्ता, स्याति एव प्रदासा के भूखे होत है। हमारे सविधान म एसी महत्वाकाक्षाओं की पूर्ति के लिए खली छट है। अपने काय काल तथा अवकाश ग्रहण करन के पश्चात यायाधीशा की काय-पालिका के क्षेत्राधिकार के अधीन किसी भी पद को प्राप्त करने की आकाक्षा पर प्रतिदाध सम्बाधी सविधान म कोई व्यवस्था नहीं हु। स्वतात्रता के पश्चात अनेक "यायाधीशा को विभिन्न पदा पर नियुक्त किया गया। 1950 ई म भूतपूर्व "याया-धीवा सी सी विद्वास को अल्पसरयक मामला का मात्री एवं 1952 ई में केन्द्रीय विधि म'नी नियुक्त किया गया था। भूतपूव यायाधीश समद फजल जली की पदा-वकादा के पदचात पहले अस्यायी वायाधीश नियुक्त किया गया था (अनुच्छेद 128) और 1952 ई में उह उडीसा का राज्यपाल नियुक्त दिया गया था। भूतपुत्र याया-धीश बी एन राव को 1948 ई म सयुक्त राष्ट्र सघ म स्यामी भारतीय प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। भूतपूर्व यायाधीश वर्धाचारी की 1948 ई मे आय कर जाच चायाधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया । बम्बई उच्च यायालय के भृतपृत्व यायाधीश श्री एन सी छागला को 1948 ई म समुक्त राष्ट्र संघ म भारतीय दल का नता, 1958 ई मे अमेरिका म भारतीय राजदूत एव तत्परचात् के द्वीय मात्री नियुक्त किया गया था। श्री हरी रामच 🛭 गोखले विधि म ती नियुक्त किये जाने के पूर्व पायाचीत रह चुके हैं। अनव यायाधीशो को विभिन्न जाच-जायोगा का अध्यक्ष नियुक्त दिया उना है। स्मरणीय है कि इस सम्मावना की तरफ शो के टी खाह न खिवजान चना ने सदस्या का ब्यान आकपित करते हुए मूल अनुब्हेद 103 म समानन माँ बन्दावित किया या। परत डा अम्बेडकर ने उनका विरोध करते हुए कहा या कि यावाधीशा का शासन द्वारा प्रमानित करने के कम ही अवसर हाउ हैं। " न्यूट है औं अम्बदकर चाप-पालिका के यथाय दायित्व क सादम मा यावाबीदा की इन प्रकार पुनर्तवुक्ति की सन्मा-बनाओं के दुष्परिणामा का सही मूल्याकन न इर नक ये। दलनान समय मे किली स्ने शासन की सफलता का बाघार उसका झावहन विदेशहर जार्बिक बाजनावा का स्कर् निया वयन है । यदि उसके कायकन स उन्दर्भित कार्ट विवाद सायातम न सर्ह है तो ऐसी दशा म यायपालिका म कानकीनका नी जिल्हा जाउन हुन्य स्थ

¹⁵ Article 124 (7)

¹⁶ Constituent Assembly Debases, Vol. III, p 259

विक होता है । 1930 40 के दशक मे इसी प्रकार का एक सवर्ष सयुक्त राज्य बन रिका मे राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डी रूजवेल्ट के यू डील कायतम सम्बाधी विधिया को सर्वोच्च यायालय द्वारा अवैधानिक घोषित करने पर उठ खडा हुआ था । अधि कोपीय (वक) राष्ट्रीयकरण एव प्रीनीपस उ मूलन विवाद भारतीय राजनीति म ऐस ही विवाद हैं। सर्वोच्च यायालय के निणया के फलस्वरूप निष्प्रमानी विधिया की वैधानिकता का जामा पहनाने के लिए शासन को भारतीय सविधान मे चार सवैधानिक सशोधन पारित करने पडे हैं। यह भी सम्मव है कि सत्तारूढ दल अपने विपक्षियों को दवाने एवं स्वयं सत्ता में बने रहने के लिए दमनकारी एवं अवाछनीय विधिया का निमाण करे। कायपालिका द्वारा ऱ्यायाधीशा की नियुक्ति के अधिकार क कारण अनेक यायाधीशा म राजनीति के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकती है और वे दलीय नेताओ एव शासन को सातुष्ट करने के लिए प्रयत्नशील हो सकते है। यह सम्मावना यायपालिका की निष्पक्षता मे जन-विश्वास की हिला देवी है। अत यह निवात आवश्यक है कि पदावकाश के परचात किसी भी यायाधीश को किसी पद पर नियुक्त करने का अधिकार कायपालिका को प्राप्त नहीं होना चाहिए। 17 इस हेतु यदि आव श्यक्ता हो तो सविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि "यायाधीशो द्वारा बडे सबत रूप म अपने विचारा को प्रकट करना चाहिए। उदाहरण के लिए, उह राजनीतिक नेताओ तथा कायपालिका की प्रश्नसा नहीं करनी चाहिए और न समकालीन किसी विषय पर अपना मत ही प्रकट करना चाहिए।¹⁸ राज्यों के उच्च यायालयो के मुख्य यायाधीशो को स्थानापन्न राज्यपाल नियुक्त करन की प्रया को भी प्रथम नहीं दिया जाना चाहिए।

न्यायाधीशो का कार्यकाल एव अवकाश ग्रहण करने की आपु

यायपालिका की निप्पक्षता, ईमानवारी एव स्वत त्रता की रक्षा के लिए यह अवश्यक है कि यायाधीशा का कायकाल दीघ अर्थात कम वढ रूप में स्वायी होना चाहिए। दीघ कायकाल के फलस्वरूप यायाधीशों को विधि सम्ब धी पर्याप्त नान हो जाता है और वे निश्चत होकर निर्मोक्तापुक अपने दायिखा का सम्मादक कर सकत हैं। सपुक्त राज्य अमेरिका के सवीच्य न्यायाधी के बादाचरण-मय त जीवन मर के लिए निगुस्त किया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन एव अधिकाश राष्ट्रमण्डलीय देवों में मी यही प्रया है। भारत के स्वाच्च सम्मादक के स्वाच्य स्वायीधी के तिया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन एव अधिकाश राष्ट्रमण्डलीय देवों में भी यही प्रया है। भारत के सर्वोच्च एव जच्च न्यायालयों के यायाधीशों को निविच्त काल अर्थात् निमारित पद निवित्त की बायु तक सदाचरण के आधार पर

18 Refer to Dr K V Rao Parliamentary Derosa) of India, 1961,

¹⁷ मृतपूत्र मुख्य यायाधीश पातजिल शास्त्री ने महास म एक बार कहा या कि गारत मे कायपालिका हारा हस्त्रक्षेप की प्रवृत्ति प्रतीत होती है ।—Hundustan Standard, Dak edition, 18th May, 1954

नियुक्त किया जाता है। इस प्रषा के विषरीत संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्यों में "यायाधीशा का कायकाल अल्प होता है जा औसतन 6 ने 9 वप तक होता है। बीमोण्ट राज्य में "यायाधीश दो वप के लिए तो पे सलवेनिया में 21 वप के जिए नियुक्त किये जाते हैं। के स्विट्जर्तिया स्व यायाधीशा का कायकाल कि वप है परत्तु अधिकाशत वे पुन निर्वाचित कर लिये जाते हैं। सोवियत इस के सर्वाच्यायात्मय के यायाधीश सुत्रीम सोवियत हारा केवल 5 वप के लिए हो निर्वाचित किय जाते हैं। मैदिसको में सवाच्यायात्मय के यायाधीश से सवाच्यायात्मय के यायाधीश से सिव्यत्व हारा केवल 5 वप के लिए हो निर्वाचित किय जाते हैं। मैदिसको में सवाच्यरण-पय त कायकाल के लिए "यायाधीशा को नियुक्त किया जाता है। हैमिल्टन "यायाधीशा के लिए सवाच्यण पय त कायकाल सम्बन्धी व्यवस्था को आधुनिक शासन में महत्त्वपूण विवास मानते थे।

यायपालिका सं सम्बाधित एक अय विचारणीय प्रश्न यह है कि यायाधीश को किस आयु पर पदावकाश ग्रहण करना चाहिए। सदाचरण पर्यंत कायकाल की आलोचना यह कहकर की जाती है कि यायाधीश परिवतनशील समाज के हप्टिकीण के साथ गतिशोलता बनाये रखने म असमय रहते है। बुद्धावस्था म 'यायाधीश की कायक्षमता भी अपेक्षाकृत समाप्त हा जाती है। जत सदाचरण पयात कायकाल की दशा में भी एक निश्चित आयु प्राप्त होने पर यायाधीश को अवकाश ग्रहण कर लेना चाहिए। यह अवस्था क्या होनी चाहिए? लास्की के अनसार सत्तर वर्ष की आयु न्यायाधीश के लिए पदावकाश की आय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। ⁰ 70 वप की आयु के परचात यायाधीशो म अपने दायित्व को समालने की शक्ति नहीं रह जाती है, मले ही कुछ यायाधीश इसके अपवाद हो । यायाधीश श्री होम्स²¹ (Mr Justice Holmes) का मत या कि "यायाधीश सामा यत बद्ध व्यक्ति होते हैं। वे सम्भवत किसी ऐसे विश्लेषण को देखते ही घृणास्पद समग्रत लगते हैं जो उनकी रुचि के अनु-कूल नहीं है और जिस वे समभने के अभ्यस्त नहीं होते हैं। यह कथन महत्वपूर्ण हैं क्यों कि यायाधीश अपने जीवन के आधार पर ही विधि की समस्याओं के स दम म अपना दृष्टिकोण बनाते हे एव जो दृष्टिकोण एक बार बन जाता है उसे बद्धावस्था म परिवर्तित करना निता त कठिन हो जाता है। अत वे अपने विचारो एव समाज के परिवर्तित दृष्टिकोण के साथ सामजस्य स्थापित नही कर पात है।

¹⁹ Garner op cat, p 729

²⁰ Lasks Grammar of Politics op cit p 550

²¹ Mr Justice Holmes Collected Papers, p 230 cited in Laski op cit, p 550

विधि का शासन तथा प्रशासकीय विधि [RULE OF LAW AND ADMINISTRATIVE LAW]

विधि का शासन

समस्त आग्ल सक्सन देशों में (इगलैण्ड, राष्ट्रमण्डलीय एव उपनिवेशीय देश तथा समुक्त राज्य अमेरिका) की विधि व्यवस्था का प्रमुख सिद्धात विधि का सासन (Rule of Law) है। इसके विषरील, यूरोप के महाद्वीपीय देशों जर्च काल, जमनी आदि में प्रशासनिक याथ (Administrative law) का सिद्धात माय है। आग्ल मापा मापी देशों में यह धारणा बलवती है कि राज्य के कमचारिया से जनता

की स्वत नता की रक्षा विधि के शासन के अत्तगत ही हो सकती है।

विधि का चासन क्रिटिस सविधान की अस्पिक सहस्त्रपूण विशेषता है। विधि के शासन का सीधासाधा अथ यह है कि इग्लैंड में विधियों का धासन है, न कि किसी व्यक्ति की निरकुश इच्छा का। विधि ही सर्वोच्च है। विधि के निम पण से कोई व्यक्ति की निरकुश इच्छा का। विधि ही सर्वोच्च है। विधि के निम पण से कोई व्यक्ति कुक्त नहीं है। ए वी डामसी की विधि के सासन की अधिकृत व्यास्था को मे प्राप्त है। डामसी के अनुसार विधि का सासन या उसकी सर्वोच्चता व्रिटिश व्यक्त्या की दूसरी प्रमुख विशेषता सम्पूच देश (विटेन) में के ब्रीय धासन की सर्वोच्चता या सस्त्रीय सम्प्रभाता है।

विदेशी प्रेक्षक (यथा न्यास्ट्रेयर, ही लोलगी, ही तोकेवरी) ग्रेट ब्रिटेन कं 'विधि के सासन' की धारणा से अत्यिषक प्रमानित थे। ही लोकेवरी ने 1836 ईं में दिवस एव ब्रिटिय प्रणातियों की तुलना की थी। वह ब्रिटिय याम प्रणाती से अत्य धिक प्रमानित था। उसके विचारा का सार तिम्म है "विधि यो सर्वोच्चता इगलैण्ड की सस्याओं की प्रधान विद्यायत है।" डायसी ने विधि के झासन की व्यास्था करते हुए उसके परस्पर सम्बर्धियत तीन स्पष्ट अय किय है।

Diccy The Law of Constitution, Ch. IV (1959), pp. 183-206
 De Tocqueville's words point in the clearest manner to the rule predominance or supremacy of the law as the distinguishing characteristic of English Institution —Diccy op. at., p. 187

(क) विधि के शासन का प्रथम अथ यह है कि किसी भी व्यक्ति को किसी कानून को मग करने के लिए देश के किमी सामा य यायालय हारा सामाय विधिक रिति से अपराधी प्रमाणित किये जाने के अभाग म कोई छारीरिक एव जायिक दण्ड नहीं मुगतना एवेगा। इसका अथ यह है कि ग्रेट ग्रिटेन मे कोई भी व्यक्ति तब तक दण्डित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने देश की किसी लिखि का उल्लंधन न किया हो। देश के शासन के स्वैच्छापूनक आवरण तथा मनमानी करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यह ज्यवस्था इस अथ म प्रत्यक ऐसी व्यवस्था से मिन है जिससे शासन के अधिकारिया को व्यापक निरकुश सत्ता या निय रण सम्बन्धी स्व विवेकी शासन के अधिकारिया को व्यापक निरकुश सत्ता या निय रण सम्बन्धी स्व विवेकी शासन के प्राप्त होती हैं। अत काउन के हाथी निरकुश शक्ति का अभाव विधि के शासन का प्रथम अथ है।

यूरोपीय देशा में कायपालिका को इनलिण्ड की तुलना में ध्यक्तियों को बन्दी बनाने, कारावास का दण्ड देने एवं देश से निष्कासित करने की व्यापक शक्तिया प्राप्त है।

(स) विधि के शासन का दूसरा अब यह है कि देण के छोटे एवं वहें सभी शामकीय कमचारी एवं अशासकीय कमचारी एक ही विधि य्यवस्था एवं एवं ही प्रकार के यायालयों के अभीन है। चीई जी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है। विधि की इरिट स सभी व्यक्ति विधि के उपर नहीं है। विधि की इरिट स सभी व्यक्ति वाच वाच है। के उपर एक ही विधि के उपर तहीं है। विधि की इरिट स सभी व्यक्ति काया है। प्रधानमंत्री वे लेकर साधारण सिपाही एवं कर एक विश्व कर राधारण किया ही एवं कर एक विश्व कर राधारण किया ही एवं कर एक विश्व कर कार्य के स्थान की किया वाच कर के लिए किसी भी अप व्यक्ति की सीति ही उस्तरदामी होते हैं। अनेक एसे उदाहरण है जबकि पायालमा हारा अधिकारियों को विधिक अधिकार क्षेत्र की सीमा का जिलक्षिण करने वाले उनके कार्यों के लिए व्यक्तिगृत व्यवस्था है। प्रयक्ति करने कार्यों के लिए विध्व प्रयास क्षित्र विश्व कराया। सीत्र है। प्रयक्ति करायों के लिए विश्व किया गया या क्षित्रहित करायी गयी है। प्रयक्त वर्षों के लिए विश्व क्षित्रहान की सीत्राधालत के दौरान किया गये अपने वर्षों कर कार्यों के लिए अधिकारी की आधाणतल के दौरान किया गये अपने वर्षों कर लिए वर्षों कर की आधाणतल के दौरान किया गये अपने

4 We mean in the second place that with us no man is above the law but (what is a different thing) that here everyman whatever be his condition is subject to the ordinary law of the realm and amenable to the jurisdiction of the ordinary tribunals "—

Dicey of at . p 193

^{3 &}quot;We mean in the first place that no man punishable or can be lawfully made to suffer in body or goods except for a distinct breach of law established in ordinary legal manner before the ordinary courts of the land. In this sense, the rule of the law is contrasted with every system of government based on the exer cut by persons in authority of wide arbitrary or discretionary powers of constraint "—Divey op ett., p 188

किसी गैर कानूनी नाय के लिए अय किसी भी साधारण ध्यक्ति भी मीति ही उत्तर दायी होता है। इगलेण्ड म सिनका एव पादिया का एसी विधिया एव यावाधि करणों से सम्ब घ होता है जिनना सामा य नागरिका से कोई सम्ब घ नहीं होता। वेकिन यह ध्यवस्था इस तथ्य से निसी प्रकार भी असगत नहीं है कि देश म सभी के लिए एक से ही कानून हैं। सैनिका एव पादिया के अपने पद सम्ब धो कुछ दायित होते है परतु इसका अय यह नहीं है कि वह सामा य नागरिक के दायित्व से बक्त सकता है।

स्मरणीय है, बूरापीय देशों की व्यवस्था ग्रेट ग्निटन से मिन्न है। उदाहरणाय, मास में नागरिका के आपसी विवादा के निजय दश की सामा य विधि के अनुसार साधारण यायालवा हारा किय जाते हैं पर तु नागरिक और झासन या किसी छास कीय अधिकारी से सम्बन्धित यदि कोई विवाद होता है तो उसका निजय विधाय प्रकार के "यायालया एव विधि — प्रशासकीय यायालयों तथा प्रशासकीय विधि — हारा किया जाता है। स्पट है कि फास में ग्निटन की मीति एक विधि व्यवस्था नहीं है और न वहा विधि एव "यायालय विषयक समानता ही पायी जाती है।

इस सदम मे एक विवाद का उल्लेख वाद्यतीय है। 1763 ई म नाथ विटन (The North Briton) नामक समाचार पत्र के सम्पादक विलक्त (Willes) ने इगलैण्ड के राजा के जायण पर टिज्यणी करते हुएकहा या कि राजा का मापण मानवता पर धोपी जाने वाली में निमल्लीस धृष्टता या तिलज्जता का उवाहरण है। लाड हैलीफक्स राज्य म नी थे। उहाने नाँच व्रिटन के लिए बारण्ट जारी कर दिय। उप साने एव समाचार-पन की प्रतियो जन्त करने के लिए बारण्ट जारी कर दिय। उप सिव श्री बुद (Mr Wood) की देखमाल म गिरफ्तारियों हुइ। कुल 49 व्यक्ति व दी बनाय गये। इनम सम्पादक श्री विलक्ष्म एव प्रकाशक सीच (Mr Leach) के अतिरिक्त अन्य सभी निर्दोध थे। विलक्ष्म ने लॉड हैलीफेस्स एव बुड पर मानहांति का मुक्तमा वायर कर दिया। यायालय ने राज्यम त्री हेलीफस्स उपसंचिव बुड को रोपी उन्दर्भ सा एव 4 हजार पोण्ड व 800 पोण्ड हर्जिन के रूप म देने का आदेश दिया तथा वारण्ट का गर काननी उत्तराय।

निधि के सासन के इस अथ का विशेष महत्व है। ग्रेण्टलएड के अनुसार विधि ने सासन के इस अथ म मिन्यण्डलीय उत्तरदायित्व को विधिक दृष्टि से निदेश्वत किया गया है। होनो सदनो या किसी सदन को राज्या के मित्रयों को पदन्युत करते की विधिक शक्ति प्राप्त नहीं है। अब मानी विधिक कर में द्विटिय सस्त के प्रति उत्तरदायों है। उस मान्य यायाययों के प्रति उत्तरदायों हैं। उस पर

⁵ Maitland The Constitutional History of England p 484

राज्य सम्बाधी किसी भी काय के लिएकोई मुकदमायाश्रमियोग चलाया जा सकताहै।

(ग) विधि के वासन का तीसरा अथ यह है कि ब्रिटेन में नागरिका के अधिकार सविधान द्वारा नियमित नहीं होते हैं अपित स्वयं सविधान ही नागरिकों के अधिकारो द्वारा नियमित होता है। बायसी के शब्दा में, "सविधान विधि के शासन की भावना से ओतप्रोत है क्योंकि संविधान के सामा य सिद्धा त (यथा-वैयक्तिक स्वत वता का अधिकार या सावजनिक सम्मेलन का अधिकार) यायिक निणयो के परिणाम हैं जि हे यायालयो ने व्यक्तिगत विवादा के निणया के मध्य व्यक्त किया है। विदेशी सविधाना में इसके विपरीत व्यक्तिया के अधिकार सविधान के सामा य सिद्धा तो के परिणाम होते हैं। ' ⁶ अमेरिका और मारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सविधान म उल्लेख है। इसका अथ यह है कि इन देशों म सविधान नागरिक के मौलिक अधि कारों की जड है। पर तु ब्रिटेन में स्थिति बिलकुल इसके विपरीत है। यहां नागरिकों के अधिकार परम्परा द्वारा पहले ही निश्चित हो गये है और इन्ही अधिकारी की रक्षा से सम्बंधित नियमा के समूह से सविधान का निमाण हुआ है। ब्रिटेन में प्राय-मिकता नागरिक अधिकारा को है, न कि सविधान को । सर्विधान का मूल नागरिक अधिकारा म है। उदाहरण ने लिए, इगलैंग्ड के सामाय कानून अयात कामन लॉ (Common Law) का यह सिद्धात या कि किसी भी व्यक्ति की सामाय अधिपन (General Warrant) के आधार पर बादी नही बनाया जा सकता था लेकिन विलकेस विवाद के निणय ने इसकी यायिक मा यता प्रदान की। स्पष्ट है, ब्रिटेन मे नागरिक स्वतातता सम्बाधी अधिकारा को अाय देशा की अपक्षा कही अधिक महत्व प्राप्त है।

सिधान के द्वारा मौलिक अधिकारा की प्रतिभू दोषपूण होती है। बामसी के अनुसार जिन देखा में वयक्तिक स्वतन्त्रता सविधान का परिणाम है वहा अधिकारों को निलम्बित या समाध्य करने की सम्भावना वनी रहती है, लेकिन जहा वैयक्तिक स्वत त्रता सविधान का भाग होती है एव देश के सामाय कानून म निहित

⁶ A third and a different sense in which the rule of law or the predominance of the legal spirit is considered a special attribute, is defined by A V Dicey in the following words 'We may say that the constitution is pervaded by the rule of law on the ground that the general principles of the constitution (as for example, the right to personal liberty or the right of public meeting) are with us as the result of judicial decisions determining the rights of private persons in particular cases brought before the courts where as under many foreign constitutions the security (such as it is given to the rights of individuals results, or appear to result the general principles of the constitution'—The Law of C ton op at no 195 196

होती है, वहीं विधिकारा को देश की संस्थाओं एवं पद्धतिया में त्रातिकारी परिवतन के अमान में नष्ट करना असम्मन होता है। उदाहरणाय, घर-कानूनी द्रग में किसी में स्थिति को बन्दी नहीं बनाया जा सकता। यह व्यक्तिको बन्दी प्रत्यक्षीकरण अधि नियम (Habeas Corpus Act, 1679) द्वारा मुर्राशत है। इसी प्रकार, वरन-धरन धारण करने का विधकार विधकार-पत्र (Bill of Rights, 1689) द्वारा मुर्राशत है। इस दोना विधेयका नो सकट काल में पूणत स्थित नहीं किया जा सकता है।

सक्षेप म, विधि के शासन व तीन अय हैं

(1) निरकुष चत्ता का अनाव एव कानून की सर्वोच्चता। 'विधि के धासर्' के अन्तगत सासन एव उसके अधिकारियों को विद्येपाधिकार एवं व्यापक स्विविकी निरकुश अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इनलण्ड म 'विधि के सासन' के अधीन व्यक्ति को केवल किसी विधि के उस्सपन के लिए ही दण्डित किया जा सकता है।

(2) विधिक समानता या विधि के समन समानता । इसका अप यह है कि देश के सभी व्यक्ति विना किसी नेदमान के एक प्रकार की विधि के अधीन होत हैं एव वे एक ही प्रकार के याधानया कं प्रति उत्तरदानी होते हैं। फान्स म प्रचितत प्रशासकीय विधि एव प्रशासकीय न्याधानया की ब्यवस्था के लिए, बायसी के अनुसार, इनलफ म काई स्थान नहीं है।

(3) इमलण्ड म सविधानिक विधि व्यक्तिया के अधिकारों का सोत नहीं है अपितु वह व्यक्तिया के अधिकारों का परिधाम है। इन अधिकारों की समय-समय पर पायानी द्वारा व्यक्तिया की मधी है एवं उन्हें किसानित किया गया है। अधिक पायामीधा ने व्यक्तिया के अधिकारों एवं स्वरंत्र नाओं की रक्षा म इस प्रकार महत्त्वपूर्ण मूमिका निनायी थी। श्री बाधसी 19वी सदी का उदारवादी था। उदारवादी याया पीदों ने अधिक जनता के अधिकारों एवं स्वरंत्रका की रक्षा के लिए जो सराहनीय प्रयत्न किय थे डायसी न उपरोक्त सत स्वरंत्र करते हुए उनकी प्रसत्ता नी है।

'विधि के तासन' के परिणामों की ब्यास्मा करते हुए बायसों ने कहा है कि विधि का तासन 'गासकीय कमचारिया की निरक्ता प्रश्नेतचे पर प्रतिवध्य स्थापित करता है। किसी विधिक वाधार के जनाव म किसी अबेच ब्रिक्शनी द्वारा किसी स्थाफि को वस्ती नहीं नगाया जा सकता क्योंकि वह यह प्रतो प्रकार चानता है कि यदि यायालय द्वारा उसके नगाई ने गर-काननी घोषित दिचा जाता है तो उसे सित-

⁷ Dicey op est p 201

³ The Rule of Law 18 with us the law of the constitution, the rules which in foreign countries naturally form part of a constitutional code are not the source but the consequence of the right of individuals as defined and enforced by the court. —Diccy op. cit., p 203

पुर्ति करनी पडेगी। अपन वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन करत समय भी . अधीनस्य कमचारी इस बात के लिए सजग रहते हैं कि वरिष्ठ अधिकारी के आनापालन के दौरान कही किसी विधि का उल्लंधन न हो जावे। यदि किसी सिपाही को किसी जन समूह की तितर वितर करने का आदेश दिया जाता है तो इसका यह अथ नहीं है कि अनावश्यक रूप से वह व्यक्तिया का वध कर दे। यदि वह कतव्य पालन के दौरान म किसी व्यक्ति को कोई शारीरिक या आर्थिक हानि पहेँचाता है या किसी व्यक्ति का वध कर देता है और वह उसके लिए दोषी पाया जाता है तो यायालय उसको अनिवायत द्वण्डित करेगा। इस व्यवस्था का शासकीय कमचारिया पर वाछित प्रभाव पडा है। अत विधि के शासन की धारणा ने अप्रत्यक्ष रूप म ब्रिटिश समाज की स्वत उता की रक्षा ने योग दिया है।

विधि के शासन के ग्रुण एव दोव⁹

डायसी के अनुसार विधि का शासन व्यक्ति की स्वत नता का सरक्षक है। अय यूरोपीय देशा की तलना म इमलण्ड म व्यक्ति की स्वत त्रता अपक्षाकृत अधिक रक्षित है। बादी प्रत्यक्षीकरण आदेश द्वारा न केवल नागरिका को अपित विदिशामा को भी अविधिक दग से बादी बनाय जाने के विरुद्ध सरक्षण प्राप्त है। सैनिक विधि का क्षेत्र सीमित है एव यायालया का इस विधि पर भी नियत्रण होता है। इगलण्ड म ज्यूरी प्रया प्रवलित है। निर्वाचन सम्बाधी विवादों का निषय याय के उच्च याया-लय (High Court of Justice) हारा किया जाता है। गम्भीर श्रीमक विवादों के तिर्णय भी उच्च यायालय द्वारा किये जाते हैं। इगलैण्ड के यायाधीशा को वडी श्रद्धा से देखा जाता है एवं व विशेष आदर के पान होते हैं।

विधि के शासन का प्रमुख परन्तु कम गम्मीर दोप यह है कि इसके अतगत कायपद्धति जटिल एव विधिकता युक्त (legalism) होती है। इससे पर्याप्त हानि वी सम्मावना रहती है।

आसोचना-प्रो डायसी न विधि के दासन की अतिदायोक्तिपूण प्रदासा की हैं। आसोचको के अनुसार इमलण्ड म डायसी के अयों म विधि का पासन नहीं पाया जाता, अपितु उसके अनेक अपवाद ब्याप्त हैं। श्री वेड (Mr Wade), सर आइयर जिंग्स (Sir Ivor Jennings) एव डब्लू ए रावसन (W A Robson) ने डायसी द्वारा प्रतिपादित विधि के धासन की घारणा की तीत्र आलोचना की है। यतमान-कालीन इमलण्ड म व्याप्त विधि के शासन की सीमाएँ स्पष्ट हैं। शासन के कायक्षेत्र म असाधारण वृद्धि हुई है। शिक्षा, स्वास्त्य, वेकारा का सरसण, नगर नियानन आदि काय राज्य के दायित्व के अन्तात वाते हैं। एसस्वरूप वनक कायपालिका व्यथकारिया को न्यायिक दामित्व सीपे गर्य हैं। यदि विधि के नासन को विनुद्ध अथ म देशा जाय

Refer to Dicey op cal , pp 394-398

752 | आधुनिक शासनतन्त्र

तो यायिक काय यायालयो के द्वारा ही सम्पादित किये जाने चाहिए परंतु ऐसा है नहीं । उदाहरणाथ,—

- (1) 1920 ई के सडक अधिनियम के अ तगत यातायात मानी को अधी मस्य कमचारियो द्वारा वसा के लाइसे स न देने सम्बाधी निणयों के विरुद्ध अपीतें सुनने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसी प्रकार, नवीन विद्यालय खोलने के सम्बाध म अपीलों को सुनने का अधिकार शिक्षा मण्डल (Board of Education) को है। काउण्टी काउ सल के निणयों के विरुद्ध अपीले सामान्य यायालय में न होकर स्वास्थ्य मनी के यहा होती हैं। यह अवस्थाएँ विधि के शासन की धारणा का उल्लावन है।
- (2) शासकीय कमचारियों को 1893 ई के सावजनिक कमचारी सरसाण अधिनियम के अधीन विशेष सरक्षण प्रदान किया गया है। इस विधि के अनुसार कियों भी शासकीय कमचारी के विरुद्ध घटना घटित होंने के 6 माह के जीतर नागरिक में मुक्तमा दायर कर देना चाहिए अयथा मामला बेक्समियाय माना जायेगा। इसके अितरिक्त यह भी व्यवस्था है कि यदि शासकीय कमचारी ने विरुद्ध अभियोग प्रमाणित नहीं होता है तो अभियोग लगाने वाले व्यक्ति को अतिर्पृत करनी पडेगी। स्पष्ट है, इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य शासकीय कमचारियों के विरुद्ध कायबाही करने के लिए साधारण जनता को हतोत्साहित करना है। अय अधिनियम मी सासकीय कमचारिया को विशेष अधिकार एव सरसण प्रवान करते है। ऐसे कुछ अधिनियम है 1902 ई का विसा अधिनियम एव 1933 ई का सावविनक अधिकार एव सरसण प्रवान करते है। एसे उद्ध अधिन स्पष्ट के सावविन अधिकार एव सरसण प्रवान करते है। एसे उद्ध अधिन स्पष्ट के सावविन अधिकार एव सरसण प्रवान करते है। एसे उद्ध अधिन स्पष्ट के सावविन अधिकार एव सरसण प्रवान करते है। से उद्ध अधिन स्पष्ट के सावविन अधिकार एव सरसण प्रवान करते है। से उद्ध अधिन स्पष्ट के सावविन के अधिकार एव सरसण प्रवान करते है। से उद्ध अधिन स्पष्ट के सावविन के अधिकार एव सरसण प्रवान करते है। से उद्ध अधिन स्पष्ट के सावविन के अधिकार एव सरसण प्रवान करते है। से उद्ध अधिकार एव सरसण प्रवान करते है। से उद्ध अधिकार एवं सरसण प्रवान करते है। से उद्ध अधिकार एवं सरसण अधिन सम्बन्ध स्थान स्वाविव स्वाविव
- (3) यायपालिका की शक्ति को सी अनेक विवादा के सम्बन्ध म सीमित कर दिया गया है। जसे गृहम नी को जिटिय नागरिकता के देशीकरण (Naturalisation) सम्बन्ध में शिल गृहम नी को जिटिय नागरिकता के देशीकरण (Naturalisation) सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र देने का निरपेक्ष अधिकार प्राप्त है। राज्य को दिसी मी ब्यक्ति को पारपत्र प्रदान करन या अस्थीकार करने का अधिकार प्राप्त है। विश्वी सासका एव राजदूती, जिल्लारीं भी यामालय म चुनीती नहीं दी वा सक्ती है। विदेशी सासका एव राजदूती, क्यार्य के क्षेत्राधिकार से उनुिक्त प्राप्त है। या वा विश्वी व्यापारिक जहांजों को यामा क्या के क्षेत्राधिकार से उनुिक्त प्राप्त है। यदि वे किसी विटिश्व विधि का उत्तयन परत हैं तो उन पर जिटिय यायालयों म कोई मुक्दमा नहीं चलाया जा सनता। किसी भी ध्यम सथ (Trado Union) एव उसके किसी अधिकारी या कमता। विश्व उसन किसी नाथ (वा विसी विचित्र या वाक्ता। विश्व उसन किसी नाथ (वा विसी विचित्र या वाक्ता। विश्व उसन किसी नाथ (वा विसी विचित्र या वाक्ता) व्यव्यात्व के द्वारा विधा या सनता है। साव्यनिक अधिनियम (1936 ई) के अधीन पुलिस ना सावजिक समाना एव जनूता की निरिद्ध पापित करा ना अधिनार प्राप्त है। पहले साम ता (Pecrs) सम्बन्धी विवादी ना निजय उनन द्वारा हो विया जाता या सेविन विषि सुपार अधिनियम (1947 ई)

के द्वारा साम तो के इस विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। लॉड चैम्बरलेन को नाटको आदि पर प्रतिब घ लगाने का अधिकार प्राप्त है और उसके इन निणया को "यापालय म चुनौती नहीं दो जा सकती है। गृहम त्री को पत्रो को रोकन एव खोलने अर्थात से सर करने का अधिकार प्राप्त है। उपरोक्त सभी व्यवस्थाएँ विधि के शासन की परम्परायत धारणा के विपरीत हैं।

- (4) इगलैण्ड म यायाधीको एव कुछ अय अधिकारियो को विशेष स्थिति प्राप्त है । उदाहरणाय, पायाधीशों को उनके उन कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठह-रामा जा सकता जो वे अपने पद सम्बन्धी दायित्वो के सम्मादन में करते है। इसका यह नियम अपनाद है कि यदि कोई अवकाशकालीन वायाधीश (Vacation Judge) अविधिक तरीके से व दी प्रत्यक्षीकरण आदेश को अस्वीकार कर देता है तो उस पर पाच सी पौण्ड क्षतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है। सीमा शुरूक एव एवसाइज अधि-कारिया को किसी व्यापारिक विवाद को सुलभाने के सम्बाध में उनके किसी काय के लिए उत्तरवायी नहीं ठहराया जा सकता हैं। यह सरक्षण उ ह सीमाशुल्क (Customs) अधिनियम (1866 ई) एव एक्साइज अधिनियम (1890 ई) के अवीन प्राप्त है। इसी प्रकार, क्रांउन द्वारा किसी भी अनुवाध (contract) को भग किया जा सकता है और सेवा सम्बंधी किसी अनुबंध (contract of services) से वह बँधा हुआ भी नहीं होता है। स्पष्ट है, अनुवाध सम्बाधी नियम या विधि काउन पर समान रूप से ब घनकारी नही है। 1947 ई के पूज तक काउन टोट (Tort)10 के लिए किसी याया-लय के प्रति उत्तरदायी नही होता था पर तु 1947 ई के काउन प्रोसीडिंग्स अधि नियम (Crown Proceedings Act, 1947) के अ तगत टोट सम्ब थी सभी दायित्वी के लिए प्राउन को भी उत्तरदायी ठहराया गया है और सामा य व्यक्ति शासन के विरुद्ध सामा य व्यक्ति की मौति ही मुकदमा दायर कर सकता है।
 - (5) सामा य यायालयों के अतिरिक्त अनेक विशेष प्रकार के यायालयों की स्थापना की गयी है। इन विशेष यायालयों के द्वारा ऐस निणय दिये जाते है जो नागरिकों के सम्पत्ति सम्ब थी अधिकारा को सी प्रमावित करते हैं। सि त्रया के द्वारा नियुक्ति अनेक विशेष यायाधिकरणा द्वारा बीमा सम्ब थी भामलों का निणय किया जाता है। सासन द्वारा भूमि हस्तगत करने पर तत्साव थी अतिपूर्ति का निर्धारण भी यही यायावय करते हैं। इसके अतिरिक्त अय प्रशासकीय मण्डलों (Boards) की स्थापना की गयी जिनके निणया के विपरीत सामाय यायालयों में कोई अपील नहीं की जा सकती। विशेष यायालयों के स्थापना एवं प्रशासकीय मण्डला को प्रवत्त यायालयों की स्थापना एवं प्रशासकीय मण्डला को प्रवत्त यायिक अधिकार विधि के शासन की इस मूल धारणा का अतिक्रमण करते हैं कि एक ही प्रकार

¹⁰ Tort means the breach of a duty imposed by law whereby some person acquires a right of action for damages

तो यायिक काय यायालया के द्वारा ही सम्पादित किये जाने चाहिए परन्तु एसा है नही । उदाहरणाथ,---

(1) 1920 ई के सडक अधिनियम के ज तगत यातायात मंत्री को अधी नस्य कमचारियो द्वारा वसो के लाइसे स न देने सम्बाधी निणयो के विरुद्ध अपीर्ते सुनने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसी प्रकार, नवीन विद्यालय खोतन के सम्बाध में अपीलों को सुनने का अधिकार शिक्षा मण्डल (Board of Education) की है। काउण्टी काउ सल के निणयों के विरुद्ध अपीले सामाय यायालय में न होकर स्वास्थ्य मात्री के यहाँ होती हैं। यह व्यवस्थाएँ विधि के शासन की धारणा का उल्लघन है।

(2) शासकीय कमचारियो को 1893 ई के सावजनिक कमचारी सरक्षण अधिनियम के अधीन विशेष सरक्षण प्रदान किया गया है। इस विधि के अनुसार किसी भी शासकीय कमचारी के विरुद्ध घटना घटित होने के 6 माह के मीतर नागरिक की मुकदमा दायर कर देना चाहिए अयथा मामला बेरूमिमयाद माना जायेगा। इसके अतिरिक्त यह मी व्यवस्था है कि यदि शासकीय कमचारी के विरुद्ध अमियोग प्रमा णित नहीं होता है तो अभियोग लगाने वाले व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करनी पडगी। सप्ट है, इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य शासकीय कमचारिया के विरुद्ध कायवाही करने के लिए साधारण जनता को हतोत्साहित करना है। अय अधिनियम भी शासकीय कनवारिया को विद्याप अधिकार एव सरक्षण प्रदान करते है। ऐसे कुछ अधिनियम हैं 1902 ई का शिक्षा अधिनियम, 1919 ई का वित्त अधिनियम एव 1933 ई का सावजिक

अधिकारी सुरक्षा अधिनियम ।

(3) यायपालिका की शक्ति को भी अनेक विवादा के सम्बंध मंसीमित कर दिया गया है। जैसे गहम नी को ब्रिटिश नागरिकता के देशीकरण (Naturalisation) सम्ब वी प्रमाण-पत्र देने का निरपेक्ष अधिकार प्राप्त है । राज्य को किसी भी व्यक्ति की पारपत्र प्रदान करने या अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है। अधिकारियों के इन निणयो को 'यायालय म चुनौती नहीं दी जा सकती है। विदेशी शासका एव राजदूती, भ तर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनके कमचारियो तथा विदेशी व्यापारिक जहाजो को यामा लयों के क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति प्राप्त है। यदि वे किसी ब्रिटिश विधि का उल्लंधन करते हैं तो उन पर ब्रिटिश यायालयो म कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। किसी भी श्रम सथ (Trade Union) एव उसके किसी अधिकारी या कमवारी के विरुद्ध उसके किसी काय (जो किसी उचित श्रम विवाद के सम्बंध में उनके द्वारा किया गया हो) के लिए कोई मुक्दमा चालू नहीं किया जा सकता है। सावजिनिक अधिनियम (1936 ई) के अधीन पुलिस को सावजनिक समाजो एव जलूसा की निपद्ध घापित करन का अधिनार प्राप्त है। पहले सामातो (Pecrs) सम्बाधी विवादी का निणय उनके द्वारा ही किया जाता या लेकिन विधि सुधार अधिनियम (1947ई) के द्वारा सामन्तों के इस विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। लॉड वैम्बरलेन को नाटका आदि पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्राप्त है और उसके इन निणयों को यापालय में चुनौती नहीं दो जा सकती है। गहमंत्री को पत्रों को राकने एवं ग्लोलन अर्थात् सन्तर करने का अधिकार प्राप्त है। उपरोक्त सभी व्यवस्थाएँ विधि के शासन की परस्परागत धारणा के विषरीत है।

- (4) इगलण्ड म यायाधीशो एव कुछ अन्य व्यविकारियो का विशेष स्थिति प्राप्त है। उदाहरणाथ, यायाधीको को उनके उन कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठह-राया जा सकता जो वे अपन यद सम्बन्धी दायित्वो वे सम्पादन में करते है। इसका यह नियम अपवाद है कि यदि कोई अवकाशकालीन यायाधीस (Vacation Judge) अविधिक तरीके से बादी प्रत्यक्षीकरण आदेग को अम्बीकार कर देता है तो उस पर पाच सौ पौण्ड क्षतिपृति का दावा किया जा सकता है। सीमा शुरूक एव एक्साइज अधि कारियों नो किसी व्यापारिक विवाद को सुलभाने के सम्बाध में उनके किसी काय के लिए उत्तररामी नहीं ठहराया जा सकता है। यह सरक्षण उन्ह सीमानल्क (Customs) अधिनियम (1866 ई) एव एक्साइज अधिनियम (1890 इ) के अधीन प्राप्त है। इसी प्रकार, काउन द्वारा किसी भी अनुबाध (contract) की भग किया जा सकता है और सेवा सम्बंभी किसी अनुबंध (contract of services) से वह वैधा हुआ भी मही होता है। स्पष्ट है, अनुबाध सम्बाधी नियम या विधि काउन पर समान रूप से ब अनकारी नहीं है। 1947 ई के युव तक काउन टाट (Tort) के लिए किसी याया लय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता या पर तु 1947 ई के काउन प्रोसीडिंग्स अधि-नियम (Crown Proceedings Act, 1947) के अ तगत टोट सम्बन्धी सभी दापित्वा के लिए नाउन को मी उत्तरदायी ठहराया गया है और सामा य व्यक्ति शासन के विरुद्ध सामा य व्यक्ति की माति ही मुकदमा दायर कर मक्ता है।
 - (5) सामान्य यायालया है अतिरिक्त अनेक विषेष प्रकार के यायालया की स्थापना की गयी है। इन विद्येप यायालयों के द्वारा ऐसे निणय दियं जाते हं जो गांगरिकों के सम्प्रीत सम्बन्धी अधिकारा को भी प्रभावित करते हैं। मन्यिमें के द्वारा गेंगुकि जनेक विदेष यायाधिकरणा द्वारा वीया सम्बन्धी भामलों का निणय किया जाता है। शामन द्वारा भूम हस्तेशत करने पर तत्सम्बन्धी सर्विपूर्त का निर्धारण भी यही यायालय करते हैं। इस्तेशत करने पर तत्सम्बन्धी सम्बन्धा (Boards) में स्यापना की गयी जिनके निष्णा के विपयेत सामान्य यायालया में कोई अपीन नहीं की जा सकती। विदेश यायालया में स्थापना की गयी जिनके निष्णा के विपयेत सामान्य यायालया में कोई अपीन नहीं की जा सकती। विदेश यायालया में स्थापना एवं प्रधानकीय मण्डला को प्रदत्त यायिक अधिकार विधि के सामन की इस भूम धारणा वा अतिक्रमण करते हैं कि एवं ही प्रवार

¹⁰ Tort means the breach of a duty imposed by law whereby some person acquires a right of action for damages

तो पायिक काय पायालयो के द्वारा ही सम्पादित किये जान चाहिए परन्तु ऐसा है नहीं। उदाहरणाथ,---

- (1) 1920 ई के सडक अधिनियम के अत्याय यातायात मात्री को अधी नस्य कमचारियों द्वारा बसो के लाइसे स न देने सम्बाधी निणयों के विरुद्ध अपीलें सुनन का अधिकार प्रदान किया गया है। इसी प्रकार, नबीन विद्यालय खोलने के सम्बाध में अधीलों को सुनने का अधिकार खिला मण्डल (Board of Education) को है। काउप्टी काउ सल के निणयों के विरुद्ध अपीलें सामाय यायालय में न होकर स्वास्थ्य मात्रे के खहाँ होती हैं। यह अववस्थाएँ विधि के शासन की धारणा का उल्लावन हैं।
- (2) शासकीय कमचारिया को 1893 ई के सावजितक कमचारी सरक्षण अधिनियम के अवीन विश्वेष सरक्षण प्रदान किया गया है। इस विधि के अनुप्तार किसी भी शासकीय कर्मचारी के विरुद्ध घटना घटित होने के 6 माह के भीतर नागरिक को मुक्तमा वायर कर देना चाहिए अयथा मामला वेक्सिमयाद माना जायेगा। इसके अतिरिक्त यह मी व्यवस्था है कि यदि शासकीय कमचारी के विरुद्ध अमियोग प्रमा चित नहीं होता है तो अभियाग लगाने वाले व्यक्ति को अतिपूर्ति करनी एडेगी। स्पष्ट है, इन व्यवस्थाना का उद्देश्य शासकीय कमचारियों के विरुद्ध कावजी करने के लिए साधारण जनता को हतो साहित करना है। अय अधितयम मी शासकीय कमचारिया को विशेष अधिकार एव सरक्षण प्रदान करते हैं। ऐसे कुछ अधिनियम हैं 1902 ई का शिक्षमा अधिनयम, 1919 ई का विश्व अधिनयम एव 1933 ई का सावजनिक अधिकार पुरक्षा अधिनियम।
- (3) 'यायपानिका की द्यक्ति को भी अनेक विवादा के सम्बन्ध में सीमित कर विया गा है। जैसे गहम नी को जिहिन्दा नागिरकता के देवीकरण (Naturalisation) समाण पत्र वे की निर्मेश अधिकार प्राप्त है। राज्य में शिक्ति मी आफि को पारम प्रमाण पत्र वे की निरमेश अधिकार प्राप्त है। राज्य में किसी मी आफि को पारम प्रमुत प्रदान करन या अश्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है। विदेशों सासको एव राजदूता, अत्तर्राष्ट्रीय सगठन एव उनके कमचारियों तथा विदेशी व्यापारिक जहाजों को यायान्यों से अंत्राधिकार से उनुमित प्राप्त है। यदि वे किसी बिट्टल विधि का उल्लाम न्या से अंत्राधिकार से उनुमित प्राप्त है। यदि वे किसी बिटला विधि का उल्लाम निर्में तो उन पर बिटिश यायालयों में कोड मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। किसी जी प्रमु सम पर्त (Trado Union) एव उसके किसी अधिकारों या कमचारी के विरुद्ध उसके किसी काय (जो किसी उधित अम विवाद के सम्बन्ध में उनके हारा किया गया हो) के विष् कोई मुकदमा चालू नहीं किया जा सकता है। सावजितक अधिनित्य (1936 ई) ने अधोन पुनित को सावजितक समाला एवं जनूनों को विधिद अधित करने का अधिकार प्राप्त है। यहले सान वार (Poes) सम्बन्ध विवाद का निषद जनके हारा ही किया जाता था से विवाद विवाद का निषद जनके हारा ही किया जाता था से विवाद विवाद विधा गुवार अधिनित्य (1947 ई)

के द्वारा सामता के इस विश्वेषाधिकार की सभाप्त कर दिवा गया है। ताट वैम्बरतेन की नाटकी आदि पर प्रतिवाध लगान का अधिकार प्राप्त है और उसके इन निणया की न्यायालय में चुनीती नहीं दो जा सकती है। गहमात्रा का पत्रा का रोकने एवं फोलन अर्घात सन्तर करने का अधिकार प्राप्त है। उपराक्त सभी व्यवस्थाएँ विधि के जासन की परम्परागत घारणा के विषरीत हैं।

- (4) इमलैण्ड म न्यायाधीको एव पुछ अप अधिवारिया का विदीप स्थिति प्राप्त है । उदाहरणाय, यायाधीचा को उनके उन कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठह-राया जा सकता जो वे अपने पद सम्बाधी दायित्वो ने सम्मादन म करते 🐉। इसका यह नियम अपयाद है वि यदि नोई अवकाशनासीन वायाधीश (Vacation Judge) अविधिक तरीक सं वादी प्रत्यक्षीकरण आदेश का अस्वीकार कर देता है तो उस पर पांच सी पौण्ड क्षतिपृति का दावा किया जा सकता है। सीमा शुरूक एव एवसाइज अधि-कारिया का किसी व्यापारिक विवाद को सुलमाने में सम्बाध में उनके किसी काय के लिए उत्तरदायी नही ठहराया जा सकता है। यह सरक्षण उन्ह सीमानुरूक (Customs) अधिनियम (1866 ई) एव एक्साइज अधिनियम (1890 ई) के अधीन प्राप्त है। इसी प्रनार, फाउन द्वारा किमी भी अनुबाध (contract) की सब किया जा सकता है और सेवा सम्बाधी विसी अनुवार (contract of services) स वह वैधा हुआ भी नहीं हाता है। स्पष्ट है, अनुवाध सम्बाबी निवम या विधि फाउन पर समान रूप से य घनकारी नहीं है। 1947 ई के पूब तक काउन टोट (Tott)10 क लिए किसी यापा-लय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था परातु 1947 ई के काउन प्रांसीटिंग्म अघि नियम (Crown Proceedings Act, 1947) के अ तमन टोट सम्बन्धी सभी वायित्वा के लिए काउन को भी उत्तरदायी ठहराया गया है और सामाय व्यक्ति शासन के विरुद्ध सामा य व्यक्ति की मौति ही मुक्तमा दायर कर सकता है।
- (5) भामा य यायालया ने अतिरिक्त अनेक विश्वेष प्रकार के यायालया की स्पापना की गयी है। इन विद्येष यायालया के द्वारा ऐस निणय दिम जाते है जो नागिका के सम्पन्ति सम्ब पी अधिकारों को भी प्रसावित करते हैं। मिन्यों के द्वारा नियुक्ति अनक विश्वेष यायाधिकरणा द्वारा भीमा सम्ब पी सामला का निणय किया जाता है। शासन द्वारा भूमि हस्तपत करने पर तत्साव पी अतिपूर्ति का निर्धारण यही यायालय करते है। इसके अविरक्त अय प्रशासकीय मण्डला (Boards) भी स्थापना की गयी जिनके निणया के विषयीत सामा य 'यायालयों म कोई अपील नहीं की जा सकती। विशेष यायालयों में स्थापना की निर्धे प्रशासकीय मण्डला की प्रदत्त यायित अधिवार दिश्वेष के श्रासक की स्थापना रिवर्ष के श्रासक की स्थापना की स्थापना स्थापना स्थापना की स्थापना स्थापना की स्थापना एव प्रशासकीय मण्डला की प्रदत्त यायित अधिवार दिश्वेष के श्रासक की है सि एक ही प्रकार

¹⁰ Tort means the breach of a duty imposed by law whereby some person acquires a right of action for damages

तो यायिक काय न्यायालया के द्वारा ही सम्पादित किये जाने चाहिए परातु ऐसा है नहीं। उदाहरणाथ,—

- (1) 1920 ई के सबक अधिनियम के अ वर्गत यातायात म नी को अधी नस्य कमचारियों द्वारा बसी के लाइसे स न देने सम्बधी निणमों ने विरुद्ध अपीले सुनने का अधिकार प्रवान किया गया है। इसी प्रकार, नवीन विद्यालय खोलने के सम्बध्ध में अपीलों को सुनन का अधिकार खिल्ला मण्डल (Board of Education) को है। काउण्टी काउपल के निणया के विरुद्ध अधीले सामा म यायालय में न होकर मचास्त्रम म जी के यहीं होती हैं। यह अयवस्त्राएँ विधि के शासन नी धारणा का उत्थान है।
- (2) "गासकीय कसवारिया को 1893 ई के सावजिनक कमवारी सरक्षण अधिनयन के अधीन विवाध सरक्षण प्रदान किया गया है। इस दिखि के अनुसार कियी भी सासकीय कमवारी के विरुद्ध घटना पटिट होने के 6 माह के मीतर नागरिक की मुकदमा दायर कर देना चाहिए अयवा मामना वैक्यमियाद माना जायेगा। इस अवित्ता दायर कर देना चाहिए अयवा मामना वैक्यमियाद माना जायेगा। इस अवित्ता तह मी ध्ववस्था है कि यदि सासक्षेप कमवारी के विरुद्ध अधियोग प्रमा जिन नहीं होता है तो अभियोग लगाने वाले व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। स्पष्ट है, इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य शासकीय नमचारियों के विरुद्ध कायवाही करने के लिए साधारण जनता नो हतीतसाहित करना है। अय अधिनियम भी शासकीय कमवारियों को विशेष अधिकार एवं सरक्षण प्रदान करते हैं। ऐस कुछ अधिनयम है 1902 ई का सिवा सविनयम, 1919 ई वा वित्त अधिनियम एवं 1933 ई का सावजिक अधिकारी सुरक्षा अधिनियम।
- (3) यायपालिका की शक्ति को भी अनेक विवादा के सम्बन्ध म सीमित कर दिया गया है। जैस गहुस नी का निर्देश नायरिक्ता के देशीकरण (Naturalisation) सम्बन्धी प्रमाण पन देने का निरपेस अधिकार आप्त है। राज्य की लिसी मीं श्व्यक्ति को गाराज करान करने या अस्तीकार करने का अधिकार प्राप्त है। अधिकारियों के इन निजया को गायाजय म जुनीती नहीं दी जा सकती है। विद्यों व्यापारिक जहाजों को पाया सम्मे से संग्राधिमार से उन्मृति प्राप्त है। यदि वे किसी जिदिश विधि का उल्लयक करते हैं तो जन पर जिदिश प्राप्त है। यदि वे किसी जिदिश विधि का उल्लयक करते हैं तो जन पर जिदिश प्राप्ताचा म कोई मुकदमा नहीं क्लाया जा सकता । किसी भी धम सप (Trado Union) एव उसके किसी अधिकारी या कमकारी के विदेश उसके किसी जी धम सप (जा किसी उचित प्रम विवाद के सम्बन्ध में उनके इत्य किया गया हो) के निए कोई मुकदमा चालू नहीं किया जा सकता है। साववनिक अधिरास (1936 ई) के अधीन पुलिस का राववनिक समालों एव जन्तुण के निपद घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। एक्ने सामालों एक जन्तुण के निपद घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। एक्ने सामाला (Peers) सम्बन्ध विवाद का निपद घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। एक्ने सामाला (Peers) सम्बन्ध विवाद का नियद चारित करने का अधिकार प्राप्त है। एक्ने सामाला (Peers) सम्बन्ध विवाद का निपद घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। एक्ने सामाला (Peers) सम्बन्ध विवाद का निपत चारके हारा है। दिया खाता या लेकिन विधि सुधार अधिनियम (1947 ई)

के द्वारा साम ता के इस विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। लॉड बम्बरनेन को नाटको आदि पर प्रतिबन्ध लगात का अधिकार प्राप्त है और उसके इन निणया को न्यापालय म चुनौसी नहीं दो जा सकती हैं। गृहमन्त्री को पत्रा का रोक्त एप छोलने अधात सक्तर करने का अधिकार प्राप्त है। उपरोक्त सभी व्यवस्थाएँ विधि क शासन की परम्परायत पारणा के विषरीत हैं।

- (4) उगलण्ड म यायाधीचा एव पूछ अन्य अधिकारिया को विशेष स्थिति श्राप्त है। उदाहरणाय, यायाधीचा को उनके उन कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठह-राया जा सकता जो वे अपने पद सम्बन्धी दायित्या वे सम्पादन म करते हैं। इसका यह नियम अपयाद है कि यदि बोई अवकादाबासीन 'यायाधीदा (Vacation Judge) अविधिक तरीने स बादी प्रत्यक्षीकरण आदेश की अस्वीकार कर देता है ती उस पर पांच सी पीण्ड शतिपति का दावा किया जा सकता है। सीमा गटक एव प्रवसाइज अधि कारिया को किसी ध्यापारिक विवाद को सुलभाने के सम्बन्ध म जनने किसी नाय के लिए उत्तरदायी नही ठहराया जा सकता है। यह सरक्षण उन्ह सीमानुस्म (Customs) अधिनियम (1866 ई) एव एक्साइज अधिनियम (1890 ई) के अधीन प्राप्त है। इसी प्रकार, फाउन द्वारा किमी भी अनुबाध (contract) को भव किया जा सकता है और सेवा सम्बाधी किसी अनुबाध (contract of services) स वह बँधा हुआ भी नहीं होता है। स्पष्ट है, अनुबाध सम्बाधी निषम या विधि पाउन पर समान रूप से बाधनकारी नहीं है। 1947 ई में पूब तक काउन टाट (Tort) 10 के लिए किसी यापा लय में प्रति उत्तरदायी नहीं होता या पर त 1947 ई के क्राउन प्रोमीडिंग्स अधि नियम (Crown Proceedings Act, 1947) के अ तबत टोट मध्य घी सभी दायित्वा के लिए पाउन को भी उत्तरदायी ठहराया गया है और सामा य व्यक्ति शासन के विन्द सामाय व्यक्ति की मौति ही मुक्दमा दायर कर सकता है।
- (5) सामाय पायालमा के अतिरिक्त अनेक बिशेप प्रकार के यायालमा की स्थापना की गयी है। इन विशेष यायालया ने हारा ऐसे निषय दिये जाते हु जो नागरिकों के सम्पत्ति सम्ब भी अधिकारा को भी प्रयादित करते है। मिन्नयों के हारा नियुक्ति अनेक विशेष यामाधिकरणा हारा बीमा सम्ब भा मामको वन निणय किया जाता है। शातन हारा भूषि हत्तमत करने पर तत्त्वम्ब भी अतिपृति वन निष्याप में यही यायालय करते हैं। इसके अनिरक्त अप प्रशासकीय मण्डला (Boards) भी स्थापना की गयी जिनने निणया के विपरीत सामाय यायालयों में कोई अभीन नहीं की जा मकती। विशेष यायालयों के स्थापना एवं प्रशासकीय मण्डला को प्रदत्त साथिक अधिकार दिश्व में अस्त साथिक अधिकार दिश्व में स्थापना है। विशेष यायालयों में इस सुल भारणा का अविक्रमण करते हैं कि एक ही प्रकार

¹⁰ Tort means the breach of a duty imposed by law whereby some person acquires a right of action for damages

विधानमण्डल द्वारा निर्मित विधि स होता हैतो ये अपन निमाधनता निनामा न हिता वी रक्षा व साधानात्र होत हैं। सभी विधानमण्डला म उच्च मध्यम यग का बहु-यत रहता है अन विधि भी हिन्द व समापता ना अप मुना स्थापार गिद्धान ना विधिन प्रशिक्ष (legal counterpart) है। यही बात बादी प्रस्केशीन एक मादन म गत्य है। यादी प्रत्यक्षीराण द्वारा व्यक्तित स्वतात्रका का रक्षा अगी अवस्था म सम्मव हा सकती है जबकि व्यक्ति विधि का (जा कि मध्यति का साया है) उत्सपन नहीं बरता है। बायसी न इस परिशय्य म विधि व शासन ना उत्साहपूरन प्रतिपादन विया है और यह उतनी ही तीत्रता स प्रभासकीय याय की निया करता है।" सास्की न इंहा विचारा का निवन राव्या म स्वक्त किया है "डावमी के विधि के पाउन का सिद्धा त एवं प्रधानकीय विधि के प्रति तीव पूणा बात हुए एतिहासिक पुन के प्रमुख तस्व। पर आपारित है । बापसी वा विधि व दासन का निद्धान्त एन आगविश व्यक्ति याद की अभिन्यक्ति है जिसम राज्य एवं नामरिक प्रस्पर जिराधी बाद सवाद न रूप में है एवं निष्यक्ष चायालय सामान्य विधि न शाहबत सिद्धान्ता न आपार पर मानुसा बनाय रसता है। समित यह शास्यत सिद्धान सा वास्तव म राज्य क निर पुरा हस्तक्षेत् । सम्पतिशाली की सम्पत्ति की रक्षा का साधनमात्र थ । इन सिशाला के तस्य (characters) स्थायी नहीं थ । इनन स्वरूप म सामाजिक दयाया न पत-स्वरूप परिचतन आत रहे, जैगा हि टाट (tort) सम्बाधी विधि के विकास म स्पव्ह है ।भ

प्रगासपीय विधि सम्बाधी मुचनाएँ द्वायशी-बालीन समाज की अपसा आज अधिर उपनत्प हैं। हाममी भी इस आलापना म विशेष बल नहीं है कि प्रयासकीय विधि व अपतांत ब्यक्ति की स्वलात्रता की रहा नहीं है। पातो है। प्रधासकीय विधि पा पातालया व अपं अनियामत निर्दुत दासन नहीं है और म इस तथ्य म ही गोई वल है कि प्रशासकीय विधि प्रणासी व अन्तमत प्रसासनिक सुविधा एव अधि कारिया के प्रति विशेष स्थान दिया जाता है। प्रधासकीय पातालया के पाताचीय क्षत्रत विधि म ही पाराल नहीं होत हैं अधितु उन्हें प्रधासकीय असुषय भी होता है

16 Refer to Dicey of cit, Introduction pp Cill IVand p CXLVI, quoted by M G Gupta Modern Governments, 1967, pp 407 408

The truth is that Prof Dicey's conception of the rule of law and his profound hostility to droit administratif were both based on the postulates of an historic period which have now passed away. His rule of law was the expression of an atomic individualism. His account moreover, of droit administratif was a caricature. "—Laski. Parliamentary Government in England, 1952, p. 355

जिसके फलस्वरूप समस्या के वैयक्तिक एव मावजनिक पक्षों के मूल्याकन में सरलता होती है। फ्रान्स में जहाँ प्रशासनीय विधि प्रणाली है, समय व्यतीत होने के साथ साथ प्रशासकीय न्यायालय शासन एव प्रशासकीय अधिकारिया के निरक्स एवं अविधिक कार्यों से ब्यन्ति की रक्षा के सबल साधन प्रमाणित हुए है। स्वय प्री डायमी के 'विधि के शासन' सम्बाधी विचारों में समय व्यतीत होने के साथ साथ परिवतन आने लगा या । अपनी पुस्तक के आठवें सक्करण की भूमिका में डायसी ने 'विधि क शासन' के प्रति निष्ठा में कमिक हास के प्रति शिकायत को है। उन्होंने दलीय शासन की दोपपुण पद्धति के विकास की विधिहीनता का एक कारण माना है। उनके अनुसार, "दलीय दासन को राष्ट्र की स्थायी बत्ता या देशमक्ति के स्थायी आदशो का प्रतिरूप नहीं माना जा सकता है।" स्मरणीय है, डायसी न उक्त विचार उदारवादी शासन-काल में व्यक्त किये थे। प्रशासकीय विधि के सम्बाध म भी उनके विचारी म परिवतन हुआ था एव उन्होन फान्स की काउन्सल ऑफ स्टट (Council of State) के यायिक कार्यों को मा यता प्रदान की थी। उन्होने यह भी स्वीकार किया था वि सामा य 'यायालय सभी प्रकार के विवादा से लोक सेवा के अधिकारिया की अटियो एव अपराधों के सम्बंध में निषय लेने वाले उपयक्त एवं थेव्ठ निकाय नहीं हो सकते । अत ऐसे निकाय की आवश्यकता है जो विधिक ज्ञान एव प्रशासकीय अनुमन स युक्त हो तथा शासन से पूण स्वत न रहते हुए उसके सदस्यगण काम कर सके 128 डायसी ने यह स्वीकार किया था कि समस्टिवाद के विकास (1906 13 ई) के साथ साथ प्रशासकीय विधि का भी विकास हवा है । वह समस्टिबाद को सच्चे लोकत न के विपरीत मानता था एव व्यक्तिवाद म उसकी पुण बास्या थी। यह समाजवाद क विकास के फलस्वरूप बढ़ी वाले आधिक टावित्वों का घोर विरोधी था तथा मिन-मण्डलीय उत्तरदावित्व उसकी इंटिट म प्रवासकीय अव्यवस्थाना के लिए न्यायालया की अपक्षा एक घटिया सरक्षण आवस्था थी।

बेड (Prof Wade) न समीक्षा के रूप म कहा है कि मापण एव समुदाय की स्वता जाता जोवत त म व्यक्ति की सकत बता की वांति ही महत्वपूण होती है क्यांकि स्वता जाता जोवत त म व्यक्ति की सकत बता की वांति ही महत्वपूण होती है क्यांकि स्वते अमात म राजनीतिक-सस्याओं एव सामाजिक अवस्था की आत्तीचना असम्मव है। निषय ही सम्वद को मापण की स्वत-तवा को सीमित करन ने अधिकार है। उदाहरण के लिए ससद हारा व्यक्ति की सम्यत्ति नी स्वत त्रता का सीमित किया जा सकता है। त्रीकिन नैयक्तिक स्वतन्त्रता का समयन सामा य दिखि (Common Law) एव प्रशासन ने विद्व ह वी प्रयागीवाण बादि हा होता है। इस व्यव म दायती का 'विधि के गामत' वा विद्वात जाज भी मिक्य है। इसन राजनीतिक स्वत त्रता वी परम्परा को जो, हमारी मबदीच सासन व्यवस्था का आयार है, व्यक्ति वताने में मार

¹⁸ Dicey of cat, Introduction, p CXIV

प्रशासकीय विधि के सिद्धा त

डायसी ⁶ के अनुसार प्रशासकीय विधि के दो प्रधान या प्रमुख सिद्धा त हैं

- (1) सासन एवं उसके कमचारियों को राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप म विरोपा-धिकार (special rights) एव उन्मुक्तियों प्राप्त होती है वो व्यक्तिया को नागरिका के रूप म प्राप्त अधिकारों एव उन्मुक्तियों से पृषक होती है। इन विशेपाधिकारों को नागरिकों के अधिकारों एव उन्मुक्तियों से पृषक होती है। इन विशेपाधिकारों को नागरिकों के अधिकारों एव उन्मुक्तियों अध्याप्त से मित्र विद्वातों पर निर्पारित किया जाना चाहिए। का सीसी इष्टिकोण के अनुसार नागरिक एव अधिकारियों की स्थित एक स्तर की नहों होती जैसे कि नामरिक एव नागरिक की स्थिति समान-स्तरीय होती है।
- (2) इन सामाय विचारों को स्वामाधिक परिणति शक्ति पुषकरण म होती है, अर्थात शासन के तीन असे विचानमण्डल, कार्यपालिका एव यापपालिका को एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में इस्तर्क्षय के अधिकार नहीं होने चाहिए । अग्रेजों द्वारा इस सिद्धा त को जो ब्यास्था को गयी है उन्नके अनुसार याथाधीश्व कायपालिका है स्वतान होते है नयोकि याथाधीश्वों को उनके पद में कायपालिका द्वारा पृषक नहीं किया जा सकता है। फ्रान्स में इसके विचरीत शक्ति पृषकरण का यह अप है कि जहां तक सम्भव हो, शासन एव अधिकारियों को सामाय यायाव्या के क्षेत्राधिकार स स्वत न हाना चाहिए और उनके जन कत्याण सम्ब धी कार्यों म यायपालिका को इस्तर्यों पत्र हो करने चाहिए के प्रकर्ण कार्यों के कार्या से मायता दी गयी थी। इस विधि के अनुसार याथाधीशा को प्रशासकीय अधिकारियों के काय में किशी तरह का हस्तर्यों करने, कमचारियों एव शासकीय कार्यों में विश्व को की की सिपद का हस्तर्यों करने, कमचारियों एव शासकीय कार्यों में विश्व को की किशी तरह का हस्तर्यों करने स्वार्या शाय शाय है। यह सिद्धां तथा या शाय के में कायवाही करने से निपिद्ध कर दिया गया था। उस समय से ही यह सिद्धां तथा या शाय के शर्म सित्य हो।

डायसी न फासीसी प्रशासकीय विधि की चार प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है ²⁸

- (1) राज्य के कमभारिया एव व्यक्तियों के संस्व ध एक पथक विधि द्वारा नियमित किये जाते हैं जो नामरिका के पारस्परिक सम्बन्ध को निर्धारित करने वाली विधि से मित्र होती है। यही प्रचासकीय विधि है। जत प्रचासकीय विधि एव सामाय विधि म स तर है जो 1800 ई से ही मा य है तथा फे च सावजितक विधि का अनि वाय जप है।
 - (2) राज्य एव प्रशासन सम्ब धी सभी प्रकार के विवादा म देश के सामा य गाया-

²⁶ Dicey op at pp 336 338

लयों को किसी प्रकार का कोई सेनानिकार प्राप्त नहीं है। अपितु एसे सभी विवादों के निषय प्रसासकीय स्वायालयों द्वारा ही निये जाते हैं। यायालया को प्रसासकीय विवादों ने निषय सम्ब भी अधिकार प्रदान करने का अन सामाय प्रस सीसी की हिन्द प्र सिंक प्रवृत्तवारों ने निषय सम्ब भी अधिकार प्रदान करने हैं। इसके अवितरिक्त कार सम्यायाधीय राज्य के सेवकों के यह सावना ज्याप्त थी कि "न्यायाधीय राज्य के सेवकों के यानु होते हैं और इस बात की सदैव सम्मावना है कि वे सावजनिक हितों की उपक्षा करते हुए शासन की सामाय कायपद्धित में हस्तकीप करें। क्रान्ति के पश्चात यायाधीयों में सामन के प्रति अपन्त विवाद में आज भी कोई क्षेत्राधिकार प्रप्त नहीं है। यायाधीयों में सामन के प्रति अपन्त विवाद में आज भी कोई क्षेत्राधिकार प्रप्त नहीं है। सासकीय कमचीरिया सम्बन्धी समस्त विवाद प्रशासकीय यायालया द्वारा ही निर्णीत किय जाते हैं और शामन की अनुमति से ही ऐस विवादों की सामाय यायालय के समक्ष विवारय प्रस्तुत किया जा सकता है। "

(3) प्रणासकीय "यायालयो एव सामा प्र यायालयो वे मध्य क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवादो के उत्पन्न होने की प्राय सम्मावना होती है। फास म इस प्रकार के विवाद का निषम विवाद "यायालय (Court of Conflicts) द्वारा निया जाता है। इसमें काउ सल ऑफ स्टेट (Council of State) एव सर्वाच्च न्यायालय—कोट ऑफ कासेसन (Court of Cassation)—को समान प्रतिनिधित्व प्रवान किया जाता है एव याय-म तो इस "यायालय की अध्यक्षता करता है। वचालियन के समय ने इस प्रकार के क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवादो वा निषम करने का अधिकार सिद्धा तत राज्याध्यक्ष को प्राप्त या पर जु व्यवहार म 'काउनसक्ष आफ स्टेट ही सर्वाच्च प्रशासकीय न्याया- लग या।

फास में राज्य कमचारी द्वारा अपने किसी विण्य अधिकारी के उचित हम से आतापालन एव सासकीय कत्तव्य के सम्यादन य किसी गलत नाय को नरने के अपराषी होने पर भी देश के सामाय यायालया को उस पर निय त्रण एवं निरीक्षण के अधिकार प्राप्त नहीं हैं ज्यात राज्य-कमचारी राज्य सम्बन्धि दायित्व एवं नाम के लिए किसी पामानय—प्यायिक प्राप्तासकीय—वे समझ उत्तरवायी नहीं होता है। इसके अविरिक्त फ्रेंच रण्ड सहिता के अनुच्छेद 114 के अनुसार राज्य-वाय के सत्तम में निरी कर्मक क्षत्र कर स्था त्रता में हस्ता में अने हैं दर्ज नहीं दिया जा सकता। इसने अविरिक्त कांच सल एक स्टंट की अनुमति के विना किसी राज्य-कमचारी ने विरुद्ध नोई भी नायवाही नहीं की जा सकती है।

'विधि का शासन' वनाम प्रशासकीय विधि डायसीॐ ने 'विधि के दासन' एव 'प्रधासकीय विधि' की तुलना वरत हुए

²⁹ Dicey op cat, pp 341-43 30 Dicey op cat, Ch XII, p 369

प्रतिनिधि के रूप से प्राामन के सम्बाध को निया जित किया जाता है। वै दूपलैण्ड म नाउन एवं उसके सेवको (अधिकारिया) की लक्ति में समय समय पर वृद्धि या ह्रास हो सनता है पर तु इन शिक्यों का प्रयाग सामा य बानून के उन सिद्धान्ता के अनुसार किया जाना आवस्पक है जो अग्रेजों के पारस्परिक सम्बन्धों को नियानित करते है। यदि कोई सासबीय कमजारी जपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर समुद हारा प्रदत्त अधि कारों का अतिमण करता है तो वह इस युटि एवं प्रमाद के लिए स्वय उत्तरदायी होता है और वह यह कह कर नहीं वच सनता कि उसने अयुक काय को अपने विर्देश अधिकारी की आज्ञापालन के लिए किया है। ऐसी किशी भी युटि के लिए इंगलैंग्ड म सासकीय कमजारी साया य यायालयों के प्रति उत्तरदायी होता है। वेदिन कास म राज्य एवं नागरिक के मध्य सम्बन्ध एक व्यक्ति एवं दूसरे व्यक्ति के मध्य सम्बन्धों का निर्धारित करने वाले सिद्धान्त से मिन्न सिद्धान्त पर आधारित है। बत प्रधासकीय विधि ब्रिटिश विधि ध्यवस्था से सब्बा भिन्न है। इनलब्ड में सामा य यायालयों एवं प्रशासकीय वायालयों तथा सामा य एवं प्रशासकीय विधि में अन्तर कास की माति न्वीकार नहीं किया गया है।

(2) डायसी का मत था कि निकट मूल म विदिश विधि में प्रशासकीय विधि का कोई समावेदा नहीं हुआ है। राज्य की शक्तियों म बिंद हुई है तथा राज्य के काय की में भावन नवीन कार्मों का समावेदा हुआ है। यद तु इन वार्मों से बिटिंग किया ध्यवस्था में प्रशासकीय विधि था विधा में हिटी किया ध्यवस्था में प्रशासकीय विधि था विधा में विधि शा विधा सावेदा है। यदि कोई विटिंग विधा समित्रीय विधि हो। यदि कोई विटिंग विधा स्थानीय याधासमा के प्रति ही चलरदायी है एवं उन जवासतों को उसकी विधिक सत्ता की निर्धारित वन्त्र का अधिकार प्राप्त है। अत इंगलण्ड के सामाय याधासमा की प्रशासन की सला को मीमित एवं उनके क्षेत्र में इन्तिक्षण करने के अधिकार प्राप्त है। अत इंगल्ड के की स्थान प्राप्त है। अत इंगली के हिंद में इंगलिंग के उसकी विधि नहीं है पर चुं 20वी सबी कं बाठवें वसक के डायली के इस मत के सहमत होना कितन है। डायमी ने यह मत आज म 60 70 वस पूत्र प्रयट किया था। इस बीच म इंगलण्ड में भी पृषक के प्रशासनीय विधि एवं याधालयां का विकास हो चका है।

प्रसासकीय विधि के गुण दोण की व्याख्या करते हुए डायसी³³ न काउन्यस ऑफ स्टेट के निपक्ष एवं महत्वपूण कार्य की प्रश्नसा की है। इसकी सत्ता एवं धार में

ऑफ स्टेट के निष्पक्ष एव महत्वपूण काय नी प्रशास की है। इसकी सत्ता एव क्षत्र में प्रति वस विस्तार होता गया है। इस यायालय में प्राय प्रत्येन फेन नागरिक की

³¹ Drost Administratif as it exists in France is the sum of the principles which govern the relation between French citizens as individuals and the administration as the representative of the Dicey of all p. 387.

^{-,} op cit, pp 398 405

सासन के विरुद्ध आवेदन के अधिकार प्रदान किये गये हैं ताकि किसी भी प्रशासनिक अधिकारों के किसी अवैधानिक काय से उसकी रक्षा हो सके । लेकिन काउन्सल ऑफ स्टट के क्षेत्राधिकार एव शक्ति में विकास के फलस्वरूप यायिक यायालया (Judicial Courts) के सम्मान एव स्थिति में हास हुआ है । डायसी की दिन्द में काउ सल के क्षेत्राधिकार म बद्धि कितनी हो लामदायक हो परन्तु उससे यायिक यायाधिकरणों (Judicial Tribunals) की सत्ता का हास होना स्वामायिक है ।

समीक्षा-प्रशासकीय विधि एव 'विधि के शासन' म कौन सी व्यवस्था श्रेष्ठ है ? आज भी विधि के शासन को अग्रेजो द्वारा स्वत त्रता का आधार-स्तम्भ माना जाता है। परन्त डायसी ने विधि ने शासन के गुणो तथा प्रशासकीय विधि के दोषो का जो उल्लेख किया है वह अतिशयोक्तिपुण है। सिद्धान्तत यह सत्य है कि प्रशासकीय "यायालयो म याय प्राप्त करना सम्मव नही है तथा व्यक्ति के अधिकारी की रक्षा भी सम्भव नहीं हो सकती क्योंकि प्रशासन विवाद म एक पक्ष म है और वही यायकती के कतब्य का सम्पादन करता है। फास म प्रशासकीय याय व्यवस्था के फिया वयन के अनुभव डायसी के उपराक्त मत से भिन्न हैं। बायसी के समय की अपेक्षा प्रशासकीय याय-व्यवस्था सम्बाधी सूचनाएँ आज अधिक उपलब्ध है। उनके आधार पर यह निविवाद सत्य ह कि डायसी के इस कथन में कोई सार नहीं है कि प्रशासकीय विधि के जधीन व्यक्ति की स्वत त्रता अरक्षित होती है। प्रासीसी प्रधासकीय विधि को वैयक्तिक स्वतः त्रता के लिए आवश्यक मानते है। फा स के प्रशासकीय पायालयों के न्यायाधीश केवल विधि म ही पारगत नहीं होते अपितु उन्हें पर्याप्त प्रशासकीय अनु मन भी होता है। फ्रांस में काउंसल ऑफ स्टट सर्वोच्च प्रशासकीय 'यायालय है। प्रारम्म म प्रशासकीय यायालया का उद्देश्य प्रशासन सम्बंधी विवादी की सामा य पायालयो के क्षेत्राधिकार सं रक्षा करना था। लेकिन गानर³³ के अनुसार फास के वतमान प्रशासकीय यायालयो का काय कासन एव उसके अधिकारियों के निरकुश एय अविधिक कार्यों से व्यक्ति की रक्षा करना है। प्रशासकीय यायालया म अधिकारी के पक्ष म किसी रियायत की गुजाइश नहीं होती है। विवादों म अपेक्षाकृत व्यय कम होता है तथा निणय भी शीछ दिये जाते है। इसके अतिरिक्त प्रकासकीय "यायालया की काय-पद्धति भी सरल होती है। सी के ऐसन के अनुसार राज्य के विरुद्ध नाग रिको को प्राप्त प्रतिकार के साधन फा स म इंगलैण्ड की अपेक्षा सरल, शीघगामी एव कम खर्चीले है। इसके अतिरिक्त प्रशासकीय यायालयो ने घासन ने विरुद्ध निणय देने में कोई सकाच या हिचकिचाहट का प्रदशन नहीं किया है। दीघवाल तक फा तीसी प्रशासकीय वायालयो द्वारा हानि के लिए जो क्षतिपूर्ति दिलायी जाती थी वह अधिक नहीं हुआ करती थी पर त अब उसमें भी नृद्धि हो गयी है। "

³³ Garner op cat p 717

³⁴ Gaudemet, quoted in Dicey op cit, p 491

766 | आधुनिक शासनत त्र

बमेरिका म बाहत व्यक्ति सामा यत् सासन के निरुद्ध कोई मुक्तमा प्रस्तुत नहीं करत हैं अपितु सम्बद्धित विस्तारियों के विरुद्ध मुक्दमा दायर किया जाता है। फास म काउ मत आफ स्टेट म हजारा ऐसे मुक्दमी को शीमतापुर्वक एवं कम तव म ही निपटा दिया बाता है। 'काउ तस आफ स्टेट अपनी निष्यक्षता के लिए विस्थात है तथा जनता को उसकी निष्पदाता म कोई स देह नहीं है।

आम के अनुसार जिटिश नागरिकों को सामाच यापासची की अपेक्षा का सीची नागरिको को प्रशासकीय यायासयो से यथाय सरसम प्राप्त होता है क्योंकि फा स में हानि पूर्ति के लिए डिग्नी छासन के विरुद्ध होती है जबकि इगलण्ड में निणय या दियो चिक्तगत रूप से अधिकारी के विरुद्ध दी जाती है और ऐसी स्पिति में उससे था (क्या थाक्रमत रूप व जापकारा क (वष्क वा जावा ए जार एवा (द्या) प्रणा वास्तविक होनि की सितिपूर्ति किन हो जाती है। ^अ इस हरिट से प्रशासकीय विधि बिटिश विधि के चासन से श्रेट्ट हैं। प्रो मोपन (Morgan) के अनुसार इंगलण्ड म प्रशासकीय विधि के सम्बंध में श्रम स्थाप्त है। सत्य तो यह है कि फास एव जमनी में राज्य के निरकुत्त एवं गैर-कानूनी कार्यों से इगलण्ड की अपेक्षा अधिक सरसम प्राप्त है। अपिद विद्यान श्री पुरुगीय ने इसी कारण यह कहा है कि प्रशासकीय यायालय व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की इंटि से सामा य यायालय की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ हैं। ³⁹ प्रचासकीय याय व्यवस्था के विरुद्ध किसी समय आगत-सम्मन देशा में जो स^{न्}रेह एवं अस तीप ध्याप्त या वह अब नहीं पाया जाता है। पानर्थ के अनुसार फेब जनता की होटि म काउसल ऑफ स्टेट (Council of State) की स्थिति अमेरिकी सर्वोच्च यायालय की स्रोति ही है जो कि स्वत त्रता का सरक्षक माना जाता है। काच छल आफ स्टेट को ऐसे सभी नियमो एवं अध्यावेशों के सम्ब ध म यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है जो विधानमण्डल द्वारा निर्मित नहीं हैं। काउ सत आक स्टेट क यायाधीशा के अय प्रशासकीय यायालया के याया धीशा की मीति अपने पद स पुषक नहीं किया जा सकता है परतु जह याय मंत्री के ब्रास परच्युत अवस्य किया जा सकता है। सिद्धात यद्यपि कासीसी प्रशासकीय विधि व्यवस्था म यायाधीस स्तत त्र नहीं होत हैं परतु व्यवहारत जन पर कोई

इधर हुछ बसों स दोनों ही अर्थात प्रशासकीय निधि एवं निधि का शासन एक दूसरे क प्रति आक्तित हो रहे हैं। इसलण्ड में अनेक प्रशासकीय यायातया का उदय हुआ है। फ्रांस म प्रशासकीय यायासयों ने यायिक वायासयों (Judicial

³⁵ Ogg English Government and Politics, P 611

³⁶ Prof Morgan quoted by Garner op at, Footnote 93, p. 721 17 Goodnow Comparative Administration Law, Vol II pp 220 21 'tical Science and Government p 722

विधि का शासन तथा प्रशासकीय विधि | 767

Courts) की काय पद्धति का अनुगमन प्रारम्म कर दिया है। का सीसी विधि सास्त्री भी एम गोडमेट के निम्म मत को उपसहार के रूप म उद्यय्त करना तकसमत होगा "प्रसासकीय विधि सोक प्रसासन के नवीन निरकुशत म फंब नागरिकों की सुरक्षा का प्रेस्टतम साधन है। काउ सल ऑक स्टेट प्रशासकीय प्राथालय के रूप म नागरिक स्वतान्ता की रक्षा पत्ति (bulwark) है। (क्रान्स मं भी) इगलैण्ड के कंप्रम ना मीति विधित सिक्ष सिक्ष हो मीति विधि सत्ता के दुरुपयोग के विषद्ध नागरिकों को न्यायाधीश सबप्रेष्ट प्रश्रा प्रदान करते है। "

³⁹ Drost Administratif "mone of the best protections of French citizen against the 'new despotism of Public Administration The conscild Etat has succeeded in establishing 'a drost administratif which is the bulwark of civil liberties. Here like common law in England, judge made law gives to the private citizens the best accurity against the abuse of power '--Prof Gaudemet Drost Administration in France, quoted by Dicey op cit, p. 491.

कुछ प्रमुख देशो की न्यायपालिकाएँ [THE JUDICIARIES OF SOME MAJOR COUNTRIES]

ग्रेट विटेस की त्याय-ध्यवस्था

ग्रेट ब्रिटेन की 'याय व्यवस्था की प्रमुख विश्लेषनाएँ निम्नवत है

(1) 'विधि के शासन' का सिद्धा त ब्रिटिश याय व्यवस्था का प्रमुख विद्धा त है, जिसका अथ है निरकुणता का लमाब एव विधिक ममानता । ग्रेट ब्रिटेन का सिन् धान मीलिक अधिकारा का परिणाम है। सभी व्यक्ति वहाँ एक ही प्रकार की विधि एव यायालया के प्रति उत्तरदायी होत हैं। जिटिश याय-व्यवस्था के अंतगत फाम की नाति प्रथक प्रशासकीय यायालय नहीं हैं। 1

(2) बिटिश याय व्यवस्था म यायक पुनरीक्षण (judicial review) की व्यवस्था का अनाव है। यायिक पुनरीक्षण के अधिकार के अधिकार वायपातिका का विधानमण्डल की विधियो एव नायपातिका के कार्यों के बारे म सर्वधानिक औषित्र सम्बन्धी निषय देने का अधिकार हाता है तथा सविधान विरोधी विधि एव काम की वहीं अवधानिक घोषित कर दिया जाता है। समुक्त राज्य अमेरिका एव मारत म यायाल्या का 'यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है लेकिन ग्रिटिश ससदीय विधि के सवधानिक औषित्र सम्बन्धी समीक्षा का अधिकार ब्रिटिश यायपातिका को प्राप्त मही है। यिटिश ससद सम्बन्धी समीक्षा का अधिकार ब्रिटिश सहित सिक्त सम्बन्धी समीक्षा का अधिकार ब्रिटिश सहित सिक्त सम्बन्धी समीक्षा का अधिकार ब्रिटिश विधिक की सी विधि की पारित कर तकती है।

(3) ब्रिटिश यामपातिका का नागरिकों के अधिकारा एव स्वत प्रता नी रहा म महत्वपुण हाथ रहा है। भारत व संयुक्त राज्य अमेरिया नी सीति ब्रिटेन म

विधि के शासन' एव प्रशासकीय विधि के विस्तृत विवरण के निए देखिए

[े]भण ने तिए देखिए बच्चाय 28।

मीलिक अधिकार सविधान द्वारा प्रवान नहीं किये गये है अपितु ग्रेट ब्रिटेन में नाग-रिको सम्ब भी मीलिक अधिकारो एवं विधि न स्वतं नताजा का उल्लेख समय समय पर दिये गय यायालयों के विभिन्न यायिक निणया में प्राप्त है। ब्रिटेन में यायालयों ने ब्रिटिश नागरिकों की स्वतं नताओं के सरक्षण का महत्वपूण काय किया है। काय-पालिका के निरकुश कार्यों के विश्वद्ध ब्रिटिश यायपालिका ने निणय देने म कभी कीई सकोच नहीं किया है। सकट काल में ससदीय अधिनियम द्वारा ब्रिटिश नागरिकों की वैयक्तिक स्वतं नताओं को समय समय पर स्थिगत किया गया है और ऐसी स्थित म यायपालिका निरोह या मूक दशक मान बनी रहती है पर तु ऐसे अवसर बहुत कम समय ने लिए ही जाये है।

- (4) जूरी व्यवस्था ब्रिटिश याय व्यवस्था की एक अन्य विशेषता है। जूरी ध्यवस्था के माध्यम से याय सम्पादन में न्यायाधीज को सहयोग देने के लिए समाज के प्रतिप्टित सदस्यों का न्यायाध्यों के साथ सम्पादन के स्वत्य जाता है। इन जूरी सदस्य कहते हैं एव न्यायाधीश सम्बचित विवाद के सम्बच्ध मं जूरी के सदस्यों की राय निगम देने के पूब जाता कर सेता है। अधिकाशत फोजवारी मामला में ही जरी सदस्य निगुक्त किये जाते है। यह आवश्यक नहीं है कि न्यायाधीश जूरी की राय को स्वीकार करे ही। ब्रिटिश न्याय ध्यवस्था में जूरी प्रणाती को महत्वपूण स्थान प्राप्त है। जूरी के सदस्य अपनी निष्यक्षता, निर्माकता, अनुभव एव सामा म ज्ञान के लिए दिय्यात होते है। अनक अवसरा पर जूरी सदस्यों ने सासन के विवद्ध मी निष्य
- (5) ब्रिटिश यायालय निष्पक्षता, स्वत नता एव निर्भीकतापूवक बाय के शीघ्र सम्पादन के लिए विग्यात हैं। वहाँ के यायावीश सामाप्यत अध्य नहीं होते हैं और उन पर याय एवं सच्चाई के अतिरिक्त अप किसी वात का प्रभाव भी नहीं होता है। यह यायपालिका की स्वत नता के कारण है। 1701 ई के सेटलभेट अदिनियम (The Settelment Act, 1701) के अन्तवय यायाधीश्रो को सदायप्यय त अपने पर पहने का अधिकार प्रधान किया गया है। स्थायी कायवाल के कारण ही ब्रिटिश यायाधीश्रो नियो मय या पक्षधात के विना ही वायित्व की सम्पादित करते आ रहे हैं। ब्रिटिश यायाधीशों को अच्छा वेतनादि भी प्रधान किया जाता है।
- (6) ब्रिटिश यायाधीशा की कायपद्धित भी सरत है। यायाधीशों को यह ब्रियंकार प्राप्त है कि वे याय के सम्मादन की कायपद्धित सम्बाधी किसी वाधा को स्वय ही हटा सकत है। सामा यत फीजदारी मामलों म वादी पर अपने पक्ष का सिद्ध करने का दायित्व होता है। अपराधी से वलपूबक बयान नहीं कराय जा सकत। गयाहा को सत्य एवं देखी हुई वात ही कहनी चाहिए। उनसे जिरह की जाती है। यायालय विवादों की सुनी खदालत म मुनत हैं।

- (7) बिटिश सायपालिना ने अधीन सम्पूण देश में एक स ही पामालय नहीं है। इसलेज्ड एव वे स (Wales) वा सायिक सगठन एक समान है। इसले विरांत, स्काटनण्ड (Scotland) में पामपालिका के खिद्धा त एव व्यवहार म नाफी अंतर है। फलस्वरूप वहीं के पामालया का सगठन मो मिन है। उत्तरी आयरलज्ड में गामालयों का सगठन महाचि निकार है। उत्तरी आयरलज्ड में गामालयों का सगठन महाचि हों। उत्तरी आयरलज्ड के गामालयों का सगठन महाचि हैं। दो पीडियों पूर्व बिटन में विमान है। इगायज्ड एव वेस्स के गामालय एककुत नहीं हैं। दो पीडियों पूर्व बिटन में विमान प्रकार के पायालय थे जिनके क्षेत्राधिकार भी परस्पर विरोधी थं। इतमें सं अनेक पायालय अनुषयोगी थे। उत्येक पायालय की अपनी कापपदित हुआ करती थी। 1873 76 ई के पायालय सन्व भी अधिनियमां हारा विटिश पाय व्यवस्था का गुनगठन किया गया है। अब सभी पायालय एक के द्रीय प्रणानी कं कथान ही और प्राचीन असमितियों एवं क्षेत्राधिकार सम्ब थी पारस्परिक विरोध का अत्त हो गया है।
- (8) बकीला की प्रेणिया एव यायाधीयों की नियुक्ति सम्बंधी प्रका भी विनिध याय यवस्था से ही सम्बंधित है। प्राय सभी यायाधीय विस्तात अधि वक्ताओं गत से प्रोडाक्यस्या प्राप्त करने पर ही नियुक्त किये जाते हैं। विटंग मं यायाधीय कि प्रवा पर किसी ध्यक्ति का उसके जीवन के आरिमक वर्षों मं नियुक्त नहीं किया जाता और न उनकी प्रवोचित की त्रीमक ध्यवस्था ही है। नियुक्त नहीं किया जाता और न उनकी प्रवोचित की त्रीमक ध्यवस्था ही है। निया प्राप्ता को के प्राप्ताधीय के प्राप्ताधीय के प्राप्ताधीय के प्राप्ताधीय के प्राप्ताधीय के कामपारिका से कि ही रियायता एवं लामा का प्राप्त करने की काई आक्षा नहीं होती है। उच्च यायात्म के प्राप्ताधीयों की पुनरावेदनीय गामालय या लांड तमा (Court of Appeal or House of Lords) के लिए प्रोतिन होने के अवसर होते हैं पर तु इसके उनकी प्रतिष्ठा या वेतन मं बीजे सी ही वृद्धि होती है। फलस्वरूप व्रिटेश गामाधीश सामन के अधीन नहीं होते की यवस्था करने मं भी नहीं हिषकते हैं। इमी कारण व सामा प्रजन्त के सरक्षक माने आते है।

अधिवक्ताओं (Lawyers) की ग्रेट बिटन य दो आण्या है विधिक परामश देन बाले मालिसिटर (Solicitors), एव बैरिस्टर (Barrister)। बरिस्टर सोलिसिटरा द्वारा तयार मामलो को पायालयां में उपस्थित करते हैं और वादबिबाद एवं तक करते हैं। सोलिसिटर जहालता म माम नहीं लेते।

विदिश विधि के प्रकार

विदिश विधिष्ठ भेकार विदर्भ म तीन प्रकार की विधियों है (1) सामाय विधिया कॉमन लॉ (Common Law), (2) सुनीति (Equity) एवं (3) सर्विधिया (Statute Law)। सामा य विधिया कॉबन ला (Common Law) का विकास लगमन आठ पूत्र प्राचीन रीति रियाजों ने कारण हुआ है। नॉमन विखय के पूत्र दिटन में कोई एक सामा य विधि प्रणाली नहीं थी। विभिन्न स्थानों पर भिन्न मिन्न विधियाँ प्रचलित थी। यायालय स्थानीय सस्थाएँ मान थे। नाँमन तथा अय अग्रेज राजाओं ने देश को एकता के सूत्र में वाधने का तिक्चय किया या विससे उनके आदेश एव आजाएँ सारे देश म मा य हो सके। यायिक शक्ति को हो इस उद्देश्य की पूर्ति का वे सवल एव सफल साधन मानते थे। वह प्रमण्णवील यायालय (Assizes Courts) तथा यायाधीशा की नियुक्तियों की गयी और वे विभिन्न स्थानों पर जाकर न्याय कराय सम्पादित करने लगे। प्रारम्भ म स्थानीय अवालतों म स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार हो विवादों का निणय किया जाता था किं जु वाद म इन यायाधीशों ने स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार हो विवादों का निणय सामा य सिद्धान्तों के आयार पर करना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार ऐसे नियमों का विवादों का निणय सामा य सिद्धान्तों के आयार पर करना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार ऐसे नियमों का विवादों का किण य सामा य सिद्धान्तों के आयार पर करना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार ऐसे नियमों का विवादों का किण य सामा या विकास हुना जो सम्भूण देश में समान रूप स लागू किये गये। यही कॉमन लॉ के उदय एव विवास का इतिहास है। कामन लॉ के प्रमाणकी पर प्रवादीशा द्वारा विक-सित निया गया था। विधि के इस एकीकरण के फलस्वरूप विदेश म सबल विधि थयदस्या वा सुप्रपात हुआ और इससे देश की जनता म विधि के प्रति आस्था का जन म हुआ एव यायाधीशा को सम्मान व प्रतिस्टा प्रति हुई।

कामन लाँ यायाधीता द्वारा निर्मित विधि हैं। एक यायाधीत के द्वारा दिये गये निषय समान प्रवार ने विवादों में यायाधीता के लिए नजीर वन जाती थीं। य राजा या विधानमण्डल द्वारा निर्मित नियम नहीं हैं। यह तो याधिक निषया का परिणाम है। यह विद्यार मणाने की मूल विधि हैं। अनुव पीय विधि (Contract Law) एय दीवानी विधि ने सामा य सिद्धाता वा कामन लों जाधार है। पहले को जादारी विधि नो लिय-वद करफ सविधिया म परिणित कर दिया गया है। मुनरों क अनुतार, 'वॉमन नों ना मी सविध्या ने गिति ने यायिक निणया के विवास को प्रतिमा के कन्तरार, 'वॉमन नों ना मी सविध्या ने नोति ही यायिक निणया के विवास को प्रतिमा के क्रवस्तर प्रतिमा के विवास को प्रतिमा के प्रतिमा के स्वत्य तथा है। 'वामक विषय (precepts) एव परम्पराजा के लिए प्रयोग किया जाता है विन्हें दीपनाल स व पन-वारों एव अपरिवतनील या स्थिर (mmutable) स्वरूप प्राप्त हो गया है। 'वामन मों हो जाउन के विरोणाधिकार, नायण एव 'म्मनना वो स्वत प्रता, सानकोय अधि-वारिया व विद्य कटिनाइया वो अविध्यक्ति एव पीजनरी मामला म नूरी-ध्ययथा व अधिनरार व नियम की अविध्यक्ति एव पीजनरी मामला म नूरी-ध्ययथा व अधिनरार रा नाधार है।

^{3 &#}x27;The common law like statutory law, in continual in the by process of development by judicial decisions — Munro, W li The Governments of Europe, 1954, p. 22.

⁴ Common law is the vast body of legal precept and usage which through the centuries has acquired binding and almost immutable character 'Obg cited V D Mahajan p 3

धुनोति (Equity) ब्रिटिश विधि का दूसरा महत्वपूण स्रोत है, सुनोति स अथ 'उन विद्याता के समूह सं है जो एव दूसरे से क्रिमक रूप स सम्बन्धित नहीं हैं नेकिन प्रत्येक सुनीति सामाय विधि (नामन ला) क किसी न किसी नियम को अधिक जित या समान बनान म योग दती है। ' समय बीतन के साय साथ सामा य विधि (कामन ला) बटिल एव अपरिनतनीय होती गयी । यायाधीरा जस परिवर्तित परिस्थितिया के अनुकूल सद्योधित न कर सक । अनेक विवादा म सामा य विधि कोई निदान न सुना सकी। उसटे कामन साँ की वटिसता के कारण अनेक विवादों में सम्बंधित पत्नों के साथ गम्भीर अचाप हुए थे। पह्रहवी सदी के कारीब साम तवाद का अन्त हो रहा या एवं नवीन अय ध्यवस्या का उदय ही रहा था। फल स्वरूप सामाजिक, आधिक एव राजनीतिक जीवन म अस्विरता व्याप्त ही गयी थी । यायाधीस सामा य विभि के आधार पर ऐसी परिस्थितियों से विवादों का समाधान करने म असफल रहेथे। कॉमन लाकी इस कभी की मुनीति के विकास ने पूर्ण किया था। सुनीति परम्परा पर आधारित न होकर अत करण पर आधारित होती है। यह इस घारणा पर आधारित होती है कि विधि को समाज के नैतिक मानदण्डो के अनुकूत होता चाहिए। मुनीति सामाय विधि की पूरक है, न कि उसकी विरोधी। स्मरणीय है कि इसलैण्ड के राजा को याय का स्रोत (fountain of justice) माना जाता है। यदि कोई पक्ष यायालय के निणय सं अस तुष्ट होता है तो उसके विरुद्ध राजा के समक्ष अपील की जा सकती है। प्रारम्य म राजा स्वय इस प्रकार की प्रायनाका की धुनता था पर हु पुनरावेदनीय प्राथनाओं की सरया म विद्व के कारण राजा ने पास लर को इत पर विचार करने का अधिकार दे दिया। चासतर बाज की माति उस समय भी यायाधील तथा राजा की परिषद का विधिक सदस्य हुंजा करता था। इत प्रकार चा तरी अदालत (Chancery Court) का विकास हुआ। चा तरी अदा लंत प्रारम्न म यायालय न होकर प्रशासनिक विसाय की माति थी । इसके द्वारा सम्बचित पक्षो को सुनकर स्वीकृत निचारी एव सामा य नान क आचार पर निणय विये जाते थे। धीरे धीरे इसके द्वारा विये गये निषयों के फलस्वरूप कुछ नियमा के सप्तह का जदम हुआ। यही मुनीति कहलाते हैं। सुनीति के विद्धा त 18वी सवान्दी के प्रारम्म तक सुनिविचत ही चुके थे। चा सलर की स्थिति यायाधीस की ही चुकी थी एव चा तरी विमाग ने यायालय का रूप धारण कर लिया था। ब्रिटेन म इस प्रकार दो प्रकार की विधियां एवं दो प्रकार के पायावयों का उदय हुवा और 1873 ई तक दिने म यही स्विति वनी रही। 1873 ई में पारित याय व्यवस्था विष

⁵ Equity consists of a miscellaneous collection of principles systematically related to one another but each tending to make this or that rule of common law more equitable than it would otherwise be —Brier J. L. Law and Government p 180 would

नियम (Judicature Act) द्वारा एकल यायिक प्रणाली की स्थापना की गयी है। इस अधिनियम के अनुसार सामान्य विधि एव सुनीति को सथुक्त नही किया गया है अपितु यह ब्यवस्था की गयी कि सुनीति एव सामान्य विधि मे विरोध की स्थिति म सुनीति सान्य होगी।

सुनीति एव सामा य विधि म अनक समानताएँ हैं, जैसे—दोना ही याया-धीवा के द्वारा निर्मित विधिया हैं। दाना था विकास अपने समय की परिस्थितिया के फलस्वरूप हुआ है यद्यपि यह परिस्थितियों मिल्ल थी। सुनीति द्वारा सामा य विधि को अधिक समीचीन वनाने एवं उसकी कठोरता तथा अभाव को कम करने के लिए सामा य विधि के नियमा ने योग दिया है।

सिविधि (Statutes) से जय ससद द्वारा निर्मित विधियों से हैं। यह विधि का प्रमुख लोत है। 19 वो सदी तक सभी दीवानी एव फीजदारी नियमों का आधार सामाय विधि एव सुनीति थी। सिविधि विकास का परिणाम नहीं है अपितु लिखित एव निर्मित है। प्रारम्भ म राजा के द्वारा विधियों का निर्माण किया जाता था। आज यह कार्य 'ससद राजा सहित' (King in Parliament) द्वारा किया जाता था। आज यह कार्य 'ससद राजा सहित' (King in Parliament) द्वारा किया जाता है। सिविधि का स्थान सामाय विधि की ठुलना से प्रमुख एव प्रधान है एव दोनों में विरोध की स्थित म सविधि माय होती है। प्राचीन विधि, सामाय विधि सुनीति एव अय यायिक निज्या को नवीन ससदीय विधि द्वारा सवीधित, परिवर्तित या समाप्त किया जा सकता है। सविधि का निमाण परस्पर विरोधी यायिक निज्यों के कारण उत्तर न गतिरोधी एव नवीन समाज की आवश्यकता एव मानवण्डों की पूर्ति हें पुनिया जाता है।

ब्रिटिश यायपालिका का सगठन

त्रिटिश यायपालिका मे 1873 ई तक एक्ख प्रणाली का अमाव था। 1873 स 1879 ई के मध्य त्रिटिश ससद ने त्याय व्यवस्था से सन्य पित अनेक विभियों को पारित किया जिनके फलस्वक्ष विभिन्न त्यायालयों का उचित सपठन किया गया तथा समान कायपद्धित की व्यवस्था की गयी। त्रिटिश त्याय व्यवस्था म तीन प्रकार के याया समा है (1) दोवानी त्यायालय (Ctvi Courts), (2) फीजदारी यायालय (Ctr minal Courts), एव (3) विशेष यायालय अर्थात श्रीवी परिषद की त्यायिक समिति (The Judicial Committee of the Privy Council)।

ब्रिटेन म दीवानी एव फौजदारी यायालया के मध्य मोटे रूप म ही अत्तर किया गया है। जनेक फीजदारी मामला की मुनवाई दीवानी यायालयो एव दीवानी मामलो की मुनवाई फौजदारी यायालयो ने होती है। इसके अतिरिक्त ग्रेट ब्रिटेन के सभी क्षेत्रा में एक समान याय स्थलस्था नहीं है। इसकेच्छ एव वेस्स के यायालयो का समठन स्कॉटर्लंग्ट एव उत्तरी आयरलेग्ड स मित है।

1 बीवानी न्यायालय (Civil Courts)—दीवानी यायालया म सवस धोटी अदानत कार्यच्टी यायान्य (County Courts) है। इस प्रकार के यायान्या की स्थापना संबत्रयम 1742 ई में की गयी थी। सम्पूण इंगर्लण्ड एवं नेस्स की 500 जिलो (Counties) में विमाजित किया गया है। इन सभी जिला को 55 सेना (circuits) म नाटा गया है। प्रत्यक सर्निट में एक कारण्ये त्यायालय होता है। प्रत्यक यायालय म एक यायाधीस नाड चा सतर द्वारा 7 वप के अनुमव प्राप्त अपि-वेताओं य से नियुक्त किया जाता है। काउण्टी यायाधीस की सहायताय दी स्वासी कमचारी—रजिस्तार (Registrar) एव वैलिक (Bailiff)—होते हैं। रजिस्तार यार लय के तिषिक का काम करता है एवं वेतिक का काम यामालम के अविशा की तामी करता होता है। काउन्ही यायालय भ्रमणशील यायालय के रूप में काय करते हैं एक नम से प्रत्येक काउच्छी म इनके सम्मेलन होते हैं। काउच्छी यायालय का निम्म भना-धिकार प्राप्त हैं

(1) मी पीण्ड तक के प्रत्य या धन सम्बन्धी या 20 पीण्ड वार्षिक प्रत्य सम्ब धी सम्पत्ति एव श्रमिको की शतिपूर्ति सम्ब धी विवाद।

(॥) 10 हजार पौण्ड से कम पूजी के विवासियापन सम्ब भी विवाद। काउण्टी यायालया के ऊपर याय व्यवस्था का सर्वोच्च वायालय (Supreme Court of Judicature) है। इसके दो माग है प्रवत, पुनरावदनीय यापालय (Court of Appeals) एवं दिनीय, उच्च यायालय (High Court of Justice) ।

(1) पुनरावेदनीय यायालय-नाउटी यायालया एव उच्च यायालया के निषयों के विरुद्ध इस यायालय द्वारा अपील सुनी जाती हैं। पुननविरतीय यायालय म मास्टर ऑफ रोहस (Master of Rolls), लाड वा सतर एव उच्च यापालय की तीन शासाओं या विनामों के तीन अध्यक्ष यायाचीस गीठ के रूप में काय करते हैं। सींह चा तलर इसकी अध्यक्षता करता है। इस यायमालय म विधि एव तच्य क प्रश्त पर हैं। अपील हो सकती है तथा यायालय की विशेष आजा से दीवानी विवादों की अितम अपील नाडसमा मे ही सकती है।

(2) उच्च पायालय—इसकी स्थापना 1873 ई के यायपालिका सम्बन्धी अधिनियम (Judicature Act) ढारा की गयी है। 1875 ई के अधिनियम ढारा इस यायालय के क्षेत्राधिकार में परिवतन किया गया है। यह यायालय प्राचीन आठ प्रकार के यायालयों से मिलनर बना है। उच्च यायालय के तीन निम्न विचाय है

(1) चा तरो विभाग (Chancery Division)—इस यायालय द्वारा उन विवादों के निषय किय जाते हैं जो पहल सुनीति यायालया द्वारा सम्पादित किय जाते थ । इसम लाड चा सलर महित 6 यायाचीश होते हैं एवं लाड ना यत्तर इसकी

(n) राजा का पीठ यायालय (The Kings Bench for the Common

Law Cases)—इसम 19 यायाधीश एव एक प्रधान यायाधीश होता है । प्रधान यायाधीश को लॉड चीफ ऑफ जस्टिस (Lord Chief of Justice) कहत है । यायालय की यही शाखा भ्रमणशील 'यायालय (Assizes Court) के रूप में फौज-दारी विवादों की मुनवाई करती है ।

(111) वसीयत, तसाक एव सामुद्रिक डिवीजन (Probates, Divorce and Admirality Division)—पुनरावेदनीय यायालय तथा उच्च यायालय का मुस्य कार्यालय लग्न मे है। लेकिन राजा का पीठ यायालय अमणशील यायालय क रूप मे फीजदारी विवादा की मुनवाई विभिन्न स्थानो पर करता है। जिस जगह यायालय की बठक होती है उस स्थान का यह उच्च यायालय मा जाता है। काउण्टी यायालय से अपील उच्च यायालय एव उच्च यायालय से पुनरावेदनीय यायालय मे भेजी जाती हैं। उच्च यायालय को अधिक धनराक्षि सम्ब धी विवादों में मौलिक क्षेत्राविकार प्राप्त है।

उच्च यायांतय के उत्पर लाइसमा है। यह त्रिटिया साम्राज्य का दीवानी एव
फीजदारी मामला में सर्वांच्च पुनराबंदनीय यायांत्रय है। लाइस्त्राः का कभी कोई
काविदेशन यायांच्य के रूप से नहीं होता है। 1876 ई म 7 आजीवन सदस्यों
की नियुक्ति की गयी थी। इह विधिक लॉड (Law Lords) या सामाय पुनराबंदनीय
लाइ—लॉड बाफ अपील इन ऑडिंकरी (Lords of Appeal in Ordinary)—की
सज्ञा वी जाती है। 1947 ई Appellate Jurisdiction Act के अधीन इनकी
सस्या बढ़ाकर 7 स 9 कर दी गयी है। इसकी अध्यक्षता लॉड चारसनर करता है, शेप
नौ यायांथीश निविचन रूप से विधि में पूज पारगत, विधि विज्ञ या प्रमुख यायांथीश
या अधिवेता होते है।

2 फीजदारी यायालय (Criminal Courts)---इगलैण्ड मे फीजदारी याया-लयो का संगठन निम्मवत है

(1) पैटी सवान्स या कोट ऑफ समरी ज्यूरिसडिक्सन (Petty Sessions or Courts of Summary Jurisdiction) । यह सबस छोटे यायालय होते हैं । सामीण कोनो एव छोटे नगरा में इन 'यायालयों की अध्यक्षता ज़िस्टस आफ पीस (Justice of the Peace) एव बडे वहरा में वेतनजोगी वण्डाधिकारिया द्वारा की जाती है । वण्डा-विकारियों की निमुक्ति 7 वण कं अनुमव प्राप्त अधिवक्ताओं में से गृह मंत्री द्वारा की जाती है, जबकि जिस्टम ऑफ पीस की निमुक्ति वांच चा सकर काउण्टी के लाड केपटीनाटों की सिमारिया पर या डची ऑफ लक्कास्टर का चा सकर करता है। दण्डा-धिकारियों को जिस्टस आफ पीस के समान ही सीनाधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त जाकिया भी प्राप्त होती है।

जिस्टिस आफ पीस एव दण्डाधिकारियों को अकेले छोटे-छोटे विवादों ना निणय करने का अधिकार होता है। वे 20 बिलिंग तक का जुर्माना एव अधिकतम 14 दिन

का कारावास-रण्ड दे सकते हैं। गम्मीर अपराधा की सुनवाई दो या अधिक जिस्स क्षांक भीत या दण्डाधिकारिया हारा ही जाती है। जब दो यावाधीय समुक्त हर से बठते हैं तो उसे Court of Petty Session कहते हैं। इस यायालय को 50 से व अवध है था वव देखार का उपकार के उपनेता एवं विवादा में 500 पीछ तक का जुमीना एवं विवाद में 500 पीछ तक का जुमीना एवं विवाद से में कारावास तथा हुछ मामलो म 1 वय के कारावास का वण्ड दने का अधिकार होता है। किसी अपराध के लिए यदि तीन माह के दण्ड का विधान है ती ऐस मामली की सुनवाई जूरी के सहयोग स की जाती है।

काउच्टी यायालय के उपर क्वाटर सैश्च का यायालय होता है। इस यायात्त्व म जूरी काउण्डी के दो या अधिक जिल्ला काँफ पीस शामिल होते हैं। बडे नगरा म क्वाटर संश स यायावयो की अध्यक्षता वेतनभोगी वरणधिकारी करता है। प्रभीर अपरायो की मुनवाई इत यायालयो में होती है एवं निम्न यायालयो निजया के विश्व अपीर्त सुनी जाती हैं। बनाटर सबस्य यायातय के एक बर म जा सन होते हैं।

(2) अमणशील यावालय (Courts of Assizes) — ये उच्च यावालय की वासात है एव वप म तीन वार प्रत्येक कान्नची नगर एव वहे नगरी म बहरूर लगात है तथा वहा याय करते हैं। सम्मूण देश को इस काय के लिए बाठ जिलों या सकिसे ए प्रथम पहा थाव करण है। चन्त्रम थ्या का थ्या का प्रथम का प्राप्त आठ प्रथम का प्रथम की पीठ वाला के पायाधीय करते हैं एवं ज़ुरिया द्वारा उनकी सहायवा की जाती है। लंदन में के त्रीय अपराधिक यायासय (Central Crumnal Court) की बठक वप मे 10 बार होती है। इन यायालया का क्षेत्राधिकार निम्नवत है

(1) अवराधिक मामलो म क्वाटर सद्यात की अपील सुनना तथा (n) बदनामी (Slander), अंद्राचार (Corruption) बादि दीवानी निवासे की सुनवाई।

अवराधिक या फीजवारी मामला म यायाधीस की स्थिति एक निषायक (Umpire) की होती है। ब्रिटिश विधि-ध्यवस्था म सत्य का पता संगाना सामाधीत का काय नहीं है। उसका उदस्य तो चयल यह देखना है कि नियम का पालन किया जाता है तथा होता पढ़ा को निष्पत्त याथ आप्त होता है । जूरी क हारा निष्प दिय जान पर सत्य तो प्रमास म मा ही जाता है। यदि जूरी क सदस्य अपराधी नी निर्दोप समन्त हैं तो विवाद वहीं समाप्त हो जीता है और यदि जगराची नो टोपी टहराया जाता है तो यामाधीन द्वारा निषय दिया जाता है। यदि यासाधीन व निष्णय स जूरी व सदस्य अवहमत हात है तो नय जूरी सदस्या व सद्द्योग स पुन विवाद नी मुनवाई की जाती है।

(3) अपराधिक वर्षोत्तीय यायात्तय (Court of Criminal Appeals)—

ववाटर सैशःस एव भ्रमणशील न्यायालयो के निणय के विरुद्ध अपीले फीजदारी या अप-राधिक अपील यायालयो में की जाती है। इसकी स्थापना अपराधिक अपील अधिनियम (Criminal Appeal Court) के अधीन की नयी है। इस यायालय में लॉड प्रधान यायापीश (Lord Chief Justice) एवं उच्च यायालय की राजा की पीठ याया-लय के कम स कम तीन यायाधीश्व होते हैं। प्रशासकीय याय अधिनयम, 1960 के अधीन इस यायालय द्वारा यह प्रमाण-पत्र दने पर कि अमुक विवाद म सावजनिक महत्व सम्बन्धी विधि का प्रश्न निहित है और लॉडसमा मी ऐसा ही अनुमन करती है, इस यायालय के अपराधिक मामला के निणय के विरुद्ध लार्डसमा में अपील हो सकती है।

लॉडसमा देश का दीवानी एव अपराधिक (फीजदारी) मामलो का सर्वोच्च "मामलय है। 1948 ई स लॉडसमा ने अपने सदस्यो पर देशद्रोह एव एस ही अ य अपराधो के लिए दण्ड दने का परित्याग कर दिया है। अस लॉडसमा को अब कोई मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अपोलीय यायालय के रूप मे लाडसमा नी अध्य क्षता लाड चा सलर करता है। लाडसमा के देवल अपोलीय लॉड या विधि लॉड ही उसके 'यायिक कार्यों मे भाग लेते है।

3 प्रीवी परिषद की यायिक समिति (Judicial Committee of the Privy Council)-प्रीवी परिषद की यायिक समिति उच्चस्तरीय अपीलीय सस्था या निकाय है। यायिक समिति का अपना इतिहास है। 1641 ई भ दीघ ससद (The Long Parliament) द्वारा स्टार चम्बर (Star Chamber) को समाप्त कर दिया गया था तथा प्रीनी परिषद के ब्रिटिश यायालयों के निणयों के विरुद्ध अपीलें सुनने के अधिकार को समाप्त कर दिया था परन्तु उपनिवेशा की अपीले सुनन के उसके अधि-कार को अक्षुण्ण रखा था। आज भी प्रीवी परिषद समुद्र पार के उपनिवेशों के लिए सर्वाच्च पुनरावेदनीय (Appellate) यायालय हे । युजीलैण्ड को छोडकर सभी उप निवेशो ने प्रीवी परिषद की याधिक समिति के पुनरावदनीय अधिकार को सीमित कर दिया है। प्रीवी परिषद की यायिक समिति की स्थापना 1833 ई के अधिनियम के अधीन की गयी है। लॉड चा सलर इसकी अध्यक्षता करता है। इसके अतिरिक्त लॉडसमा क विधि लॉड इसके सदस्य होते हैं। एक न्यायाघीश विवाद स सम्बिधत उपनिवेश का होता है तथा कूछ ऐसे सदस्य भी होत ह जो पहले यायिक पदो पर काय चुकते हैं। लॉडसमा के विधि लाड इस समिति की सदस्यता के कारण प्रीवी पापद (Privy Councillors) के नाम से पुकारे जाते हैं। युद्ध काल म सम्प्रण साम्राज्य के नौ सनिक यायालयो का यह सर्वोच्च वायालय भी होता है। इसक जितरिक्त धार्मिक यायालय (Ecclesiastical Courts) भी इसके क्षेत्राचीन होते है। प्रीवी परिषद की चायिक समिति एतिहासिक दृष्टि से चायालय नहीं है अपित एक

ऐसी सस्या है जो राजा को याय काय म परामस देती है। व्यवहार म उसके परा मरा को ब्रिटिश राजा अनिवायत स्वीकार कर केत हैं।

समीक्षा—िनिटिस याय व्यवस्था की निष्यशता एव दसता की मरासा की जाती है। यह प्रवसा एक सीमा तर ही सही है। यह सत्य है कि अग्रेजा को वैगतिक एव राजनीतिक स्वतंत्रता जिम सीमा तक प्राप्त है वह अस देसी व नामरिका की प्राप्त प्रभागाण प्रवा तथा विभा वाना वाना वान आप हे पह जा प्रवास प्राप्त का प्रवास करते हैं। है वर ते आप एवं विभिन्न किया का ही कवल महत्व नहीं होता है असली महत्व ती विधि का होता है। त्रिटिश विधि एवं याय व्यवस्था में त्रिटिश बामपंभी विधा रको एव लेखको (जिनम लास्को एव मोध्स के नाम अन्नणी हैं) ने तीव वालो नाम की है। उनके अनुसार त्रिटिश विधि एवं याय ध्वनस्या का प्रवासार सम्मति धारण का मिद्धा त है। जिटिस विधि पूजीवादी अथ व्यवस्था का जणवार प्रणाणा गांगा गां त्रापति का है। सम्प्रति सम्बाधी कानून महत्वपूर्ण विधि है। विधि के निर्माता एव आस्याता पूजीपति होते हैं तथा उनका आधार एवं तस्य व आदा संपति प्रधान हीता है। प्रिटिश निष्धायो व यायिक सक्ति पूजीपति वस एव उनके प्रतिनिष्धिमें के होषों में होती है। ब्रिटिश वकील समाज का हिटकीण भी पूँजीवादी होता है। व पूजीवादी विधि व्यवस्था को प्राकृतिक एव स्थायी मानते हैं। जनकी हृद्धि म वैयक्तिक सम्पत्ति अक्षुण्ण है एव बासन को जसम हस्तक्षप का कोइ अधिकार नहीं है।

बिटिश विधि पूजीवादी भीतिक सम्बन्धा पर आधारित है एवं पूजीपतियो को सरक्षण प्रदान करती है। अत जिटिहा विधि का स्वरूप वर्गीय है। यह समाज म तम्मति हे स्वामियो को सरक्षण प्रदान करती है और सम्मतिशाली दग एवं उसके स्वायों को सरक्षण प्रवान करती है। लास्की एवं प्रीस ने बिटिस विधि एवं पाय-व्यवस्था के वर्गीय चरित्र का उल्लेख किया है। स्मरणीय है कि विधि के वर्गीय चरित्र का यह तास्पय नहीं है कि विधि का कोई सामाजिक पक्ष ही नहीं होता है। ब्रिटेन हैं सदम में विधि के वर्गीय चरिन से यह अब है कि ब्रिटिश विधि द्वारा बहुत्वर वम के हिता को केवल आधिक सरक्षण प्रदान विधा जाता है तथा कुछ रियायते मी जाती है जिससे कि समाज में विज्ञोह एक कार्ति न ठठ खडी हो। अधिकास विधिया प्रजीपतिया के हिता के अनुक्षम सुधार किया जाता रहा है। स्टुबटकालीन इंगलण्ड म निर हुस राजत न के निरुद्ध मध्यम वग के विद्रोह के एनस्वरूप न दी प्रस्कृतिकरण (Habcas Corpus) की स्वीकार किया गया था। जूरी श्रमा एव यायाधीवा की स्वत जाता साम ती एवं निरहुस राजत त्र के विरुद्ध मध्यम वग की सफल नाति के परिणाम थे। ब्रिटिस विधि का अधिकाश माग उम्रीसवी सदी के औद्योगिक विकास का परिणाम है। आपु निक पूजीवादी राज्य की स्वापना एव विकास के दौरान ही ब्रिटिस विधि की प्रक्रिया मी निर्मारित हुई थी। बिटिश विधि व्यवस्था मुख्य रूप स पूर्वीवादी वेग सम्बच्छी एव

⁶ Laskt Parliamentary Government in England 1952 Ch VII, pp

व्यक्तितन मकानि के अधिकारा की सरक्षा पर आवारित है एवं सामा व विधि (Con) mon Law) का भी मम्पत्ति के अधिकार के रक्षाय ही उपयोग किया गया है। मम्पत्ति के अधिकार की रक्षा की चिता समद की अपक्षा क्रयालयों को अधिक रही है। परान निषया में व सम्पत्ति के अधिकार की रक्षा में सहायक नजीरों को खोजते रहत है। यायालया न श्रमिका की अपक्षा सम्पत्ति के स्वामिया ना ही अधिक पक्ष

कल प्रमुख दशा का यायपालिकाए । । । । ४

लिया है तथा श्रीमका की परस्परागत कानन में सुधार की माग को अस्वीकार किया है। आवश्यकता पड़न पर सम्पत्ति के स्वामियों के पक्ष में विधि म परिवतन तक विध

गये है. उदाहरणाय-प्रीस्टले बनाम फाउलर विवाद । म्बरणीय है कि ब्रिटिश माधाज्य विधि के अनसार नौकर की गलनी से हान वाली हानि का हजाना मालिक को भरना पडता था। पर त उक्त विवाद में "वायवालिका न यह निणय दिया था कि प्रीस्टले अपने नौकर फाउलर की गलती के लिए हर्जान का देनदार नहीं है नयोंकि उक्त निमम से स्वामियो पर नवीन एव अनिश्चित दायित्व का जात है। यह निणय एक शताब्दी तक नजीर बना रहा । 1948 ई म धमस्तीय शामन न एक विधि . वनाकर इस नियम का जात कर दिया है। सम्पत्तिशालिया के पक्ष मे एक दूसर निणय से एकाधिकारी (monopoly) सगठन को मा व ठहरावा गया है 18 टम्परटन बनाम रसंल विवाद में न्यायालय न श्रमिको की हडताल को गर कातनी साजिक ठहरात हुए उद्यागपति को टेड युनियन से हर्जाना दिलवाया था ।" ब्रिटिश विधि व्यवस्था की हुप्टि म ध्यमिका द्वारा हडतान का अनुचित एव एकाधिकारी व्यवस्था की व्यायसगत हह-राया गया है ।

ब्रिटिश सामा य विधि10 एव याय-व्यवस्था म निहित सम्पत्तिशानी यग के पक्ष में अनेक उदाहरण दिय का सकत है। यायालया द्वारा नसदीय विधिया की समीना व्यापारिक एकता नी वानस्यकताओं को ध्यान म रख कर की जाती रही है । उपराक्त कृत्र उदाहरणो क अतिरिक्त 1910 ई का ओस्वोन¹¹ विवाद (Osborne Case) इसी प्रकार का उदाहरण है । इस विवाद म यायालय द्वारा यह निणय दिया गया कि श्रमिक-संघा क काम से राजनीतिक उद्देश्या के लिए धन व्यय नहीं दिया जा

7 Priestley v Fouler 8 Mogul Steamship Co v Mac-Gregor

Taft Valve Case, (1901) A. C 426

9

'The tradition of common law, it is important to note, has been 10 predominantly shaped by the need to serve the wants of a bust ness civilization founded upon a doubt of positive action by government Acts of Parliament are scrutinized in terms of that tradition' Lasks op cit p 363 11 Osborne Case, (1910) A C 87 इन फनस न निषय को 1911

संसदीय विधि द्वारा रह कर दिया गया।

780 | आधुनिक शासनत त्र

चकता। स्मरणीय है कि पूजीपतिया ने सस्याना हारा टोरी एवं निवस्त दता न निर्वाचन नोप म धन देना उनकी हिन्दू म अनुनित नहीं या । एक दूनरे निर्वाद राज्य वनाम हुन्¹² म यावालय ने पायूलर वरो कांच सल (Popular Borough Council) हारा सामा य विधि कं अनुमार अभिका कं लिए वतन निर्मास्ति करने कं अधिकार के सम्बाध म यह निषय दिया या कि चार बीच्ह सामाहिक का युग्तम बेतन निया प्रकार में यह शिवस क्षेत्र के हुआ कि स्ववहार में ससदीम विधि हारा बरो को प्रदत्त श्रमिका के जुनतम नेतन निर्धात्ति करने के अधिवार का प्रयोग हाउस आफ लाड हारा किया गया १३ ज्यरोक्त जराहरणा सं यह स्पट है कि यायणात्का का लक्ष्य नवीन विद्यायों को प्राचीन विचारों से जोडना रहा है। 1933 स 1935 है म पास्मोर बनाम एतिस[ा], डक्न बनाम जो स एव वामस बनाम सानि स विवादा म प्रधानयों ने पुलिस को नयी बक्तियों प्रदान की ताकि श्रीमक भा दोसना की दबाया जा सके।

बिटिश यायाधीयों के विचार भी अनुवार रह है। 1935 ई के एक विव रण के अनुसार 58 यायाधीयों म से केवल 8 न सामाय स्कूला म सिसा पायी थी, चेप समी पहिलक स्कूला की उपन थे। यागाधीस वनने के प्रव अभिकास तावजनिक राजनीतिक जीवन विता चुने थे। 1951 ई. म लाड सिमी उस. (जा पुनरावदनीय यायालय क यायापीस के) न यायापीस के पद सं इत्तीपा देकर अनुवारस्वीय मि तमण्डल में लाह चा सलर का पर यहण किया था। तास्की क अनुसार ब्रिटिश यायाधीशों का अधुनिक प्रधासन के प्रति हिन्दकोण' समुतापूण है। विधि के शासन की उहाने इस प्रकार ब्यारया की है जैसे वे ही उच्च विधि के स्वामी है, न कि सर्वोच्च विधानमण्डल । इति ही इसकी स्वीकृति एव उद्देश्य को निर्धारित करते हैं। यह महना अतिरायोक्तिपूण नहीं होगा कि वे (यायाधीय) आधुनिक राज्य की ब्याख्या करते हैं और उनकी व्याख्या भी आदत तथा पद्धति ऐसी होती है जो उन अनेक वर्देश्यों के मौचित्य को अस्वीकार कर देती है जिनके तिए रामसता प्रयत्नशीस होती है।

निहिश्च मायाधीया ने लास्की क अनुसार अपने निषया द्वारा सामाजिक परि वतन की गृति को भीमा किया है। उदाहरण के लिए, उनक द्वारा आवास विधान के

¹² Roberts v Hopwood, (1925) A C 578 13 Lasks op at p 364

¹⁴ 15

Pasmore v Elius (1932) 2 K B 134 The whole ethics of their approach is one of hostility to the And whose etnics of their approach is one of nostiniy to the process of modern administration. They interpret rule of law as them. inotess of modern administration. They interpret rule of though they are themselves the masters of a higher law that of a soveriegn legislature. —Lasks of a higher law than

क्षेत्र को पर्याप्तत सीमित कर दिया गया है। उनका सिद्धात नये अत्याचारत न (New Despotism) से नागरिक स्वत नता की रक्षा करना रहता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति के मुरय कारण निम्नत है

(1) अधिकाश यायाधीशो का पुनाव सफल वकीलो म से किया जाता है और सफ्त वकील वही व्यक्ति होता है जो अपना अधिकाश जीवन सम्पत्तिशालियों के ब्रितो की रक्षा म व्यतीत करता है।

(2) इसलैण्ड म वकीलो की शिक्षा चौद्धिक उपलब्धि की अपेक्षा सामाजिक काय अधिक है। आस्टिन के पश्चात ब्रिटिश यायशास्त्र में कोई विकास नहीं हुआ है और न यायिक सस्यानों के पुनवहन का प्रयास ही किया गया है।

(3) इमलैण्ड में यायाबीश श्रिटिश समाज मे व्याप्त एक शताब्दी पुरानी मनोवत्ति को ही अभिव्यक्त करत है।¹⁸

उपरोक्त आलोचना के होते हुए भी यह स्वीकार करना होगा कि 1688 ई के पश्चात ब्रिटिश यायाधीको की स्वत त्रता एव चरित्र स देह स परे रहे है। एक यायाधीश लाड मैकलिसफील्ड, को छोडकर किसी भी यायाबीश का चरित्र 1701 ई के पश्चात स⁻देहजर्नेक नही रहा i स्वय लास्की यह स्वीकार करता है कि व्यक्तिगत रूप से "यायाधीशो द्वारा पश्चात्ताप के मामलो की सख्या आई दजन से अधिक नहीं है। 17 भाषण, प्रशासन एवं राजनीतिक स्वतं नताओं की हृष्टि सं इगलण्ड आज भी अग्रगणी है। इगलण्ड म अमेरिका की तरह सीनेटर मैकाथीं के पुर जैसा समय कभी नहीं आया है। साम्यवादी दल को बहा अनेक देशों में अधिक स्वतात्रता प्राप्त है। बिटिश याय व्यवस्था म बादी प्रत्यक्षीकरण तथा जुरी प्रणाली का के द्रीय महत्व है। यह दोनो सस्याएँ लोकत न की रक्षक हैं। इगलैण्ड म ब दी प्रत्यक्षीकरण की व्यवस्था 1679 ई से है। आपातकाल, उदाहरण के लिए दा विश्वयुद्धी का काल, मे व दी प्रत्यक्षी-करण की व्यवस्था को स्थिगत कर दिया गया था। जुरी व्यवस्था ने नागरिक जाजादी की रक्षा की है। पर तु कुछ विचारक इसकी तीव आलीचना यह कह कर करते हैं कि अधिकारा सदस्य प्रौढ मध्यममार्गी एव मध्यमवर्गाय होते हैं। व उच्चवर्गीय सामा-जिक व्यवस्था से प्रभावित होते है अत उनके विचारा में मी यही प्रवृत्ति भलकती है। ब्रिटेन से प्रशासकीय चाथ व्यवस्था

द्वायसी के कथनानुसार ब्रिटेन में प्रशासकीय विधि नहीं है। परनु डायसी का यह कथन सत्य नहीं है। फाइनर का कथन है कि जहां प्रसासन तथा विधि होगी वहीं प्रशासकीय विधि का होना अनिवाय है। गै रोवसन के अनुसार ब्रिटेन में ऐसी अर्थात

¹⁶ Lasks op at pp 372 374

¹⁷ Ibid p 361

¹⁸ Finer op at , p 924

प्रशासनीय विधि है। इसन मुख्य लात हैं सविधि या सामा य विधि, सुनीति एव कायपालिका कं अमा द्वारा अपन दायित्व-सम्मादन के दौरान निमित्त विधियों। अनि समय एवं प्रत्यार्षे भी प्रशासकीय विधि की सर्वधानिक विधि की मिति ही महत्त्व प्रण माग है।19

घट त्रिटेन म बहुत स प्रसासकीय यायात्वय हैं जिनका श्राकरिमक विशास हुआ है। य यायानय फासीसी याय व्यवस्था है। यीत निर्देश याय-व्यवस्था क क्षण है। य वायाच्य वावाचा वाय व्यवस्था या वावा । वाव्य व्यवस्था का नहीं है। बेट बिटेन य प्रधासकीय वाय-व्यवस्था का प्रारम् 1875 ई 1888 ई म गठित रेलवे एव नहर आयोग की स्थापना से रोबसन के अनुसार, प्रशासकीय याव व्यवस्था का प्रवाह प्रारम्ब हुआ है। वतमान सदी के प्रारम्ब हे पासन के कार्या एव वायित्वा म वृत्वि हुई है। घासन का समाख वे आपिक एव सामाजिक जीवन सम्बंधी समस्याभी सं अधिकाधिक सम्बंध स्थापित होता गया। ब्रिटिश संसद इन समस्याओं के सम्बन्ध म समयामान के कारण विधि मही बना सकी थी । 1920 ई वक विभिन्न महासकीय यायाधिकरणा (यथा स्वास्थ्य म त्री, ध्यापार मण्डल (Board of Trade), जिल्ला म जालय, गहुम त्री, विद्युत आयोग, जिला लेखा परीक्षक) को अनेक याधिक वासित्व सीचे गये है। इसके अतिरिक्त निसदस्यी यायाधिकरणा की स्थापना भी हुई थी। ब्रिटिस ससद ने नगर एव ग्रामीण नियोजन विक्षा, स्वास्त्य सेवा, पुलिस आहि मामलो में सम्बन्धित विमानीय मिन्नया को ससदीय विधि के अधीन ध्यापक शक्तियाँ प्रदान कर दी हैं। प्रशासकीय लयो की सप्या दो हजार हे भी अधिक है एवं विगत कुछ वर्षों म जनके कार्यो विद्व हुई है। त्रिटिस सम्बोग संविध द्वारा गठित प्रचासकीय पागालया के निष विरुद्ध सामा यतः कोई अपील नहीं होती है। परंतु 1958 ई के यायाधिकस्य जीच अधिनियम (Tribunals and Enquiries Act 1958) के अतगत इंग्लर उच्च यायालय म एव स्काटलण्ड के लक्षन यायालय (Court of Session) प्रवासकीय पापालयों के निषयों में विधि संस्वाधी प्रकृत निहित होने पर पुनरावर (Appeal) की सबस्या है। म त्री के निषया क विरुद्ध विशिष्ट पुजरावेदनीय साया त्यों में अपीलें की जा सकती हैं। विभिन यायाधिकरणा तथा उनके प्रतिवेदनों का यायाधिकरण समिति (Council of Tribunals) हारा निरीक्षण किया जाता है।

प्रेंट प्रिटेन म निम्न प्रकार के प्रशासकीय यागालय वागे जाते हैं

(1) यातायात एव गूमि यायाधिकरण (Transport Tribunal and Lands Tribunals)—इसकी सहस्यता स्थामी है एवं सदस्यगण विद्यप योग्यता सम्पन्न होते है।

- (2) कुछ यायाधिकरण विश्वद्ध रूप से प्रशासकीय होते हैं, जैसे—आय-कर के विशेष आयुक्त (Special Commissioners of Income tax) । यह अधिकारी वेचल आय-कर सम्बन्धी विवादों का ही निषय करते है ।
- (3) ऐसे "यायाधिकरण जिनका सम्ब घ एक ही शासकीय विमाग से होता है। उदाहरणाय—नेशन अपील "यायाधिकरण आदि।
- (4) सामा य स्यक्तियों से सम्बद्धित विवादों के निणय हेतु मित्रया द्वारा गठित यायानिकरण, जसे —िकराया यायालय ।

वतमात परिस्थितियों में प्रशासकीय विधि एवं याय व्यवस्था की अनिवायता को स्वीकार करते हुए भी ब्रिटिश प्रशासकीय याय व्यवस्था में सुधार के प्रयस्त किये गये हैं। प्रशासकीय विधि व्यवस्था के सामा य दोष निम्नवत है प्रशासकीय यायालय में सामा य यायालयों की यायिक पद्धति एवं नियमों का अनुमगत नहीं किया जाता है, निणय प्रकाशित नहीं कियं जाते हैं और अधिकारी को अपने निणय के सदम में कारण बताने की आवश्यक्त गहीं होती। प्रशासकीय यायाधिकरणा के निणया के विच्छ अपीक की बाधित सुविधाएँ नहीं है। इन दोषा के रहते हुए याय की आशा करना व्यव है।

1929 ई में लाड हीयह ने अपनी पुस्तक 'तवीन निरकुशवाद' (New Despotsn) एव पोट की पुस्तक 'प्रशासकीय विधि' (Admunistrative Law) तथा ऐलन की पुस्तक 'विजयी नौकरशाही' (Bureaucracy Trumphant) में प्रशासकीय याय एवं विधि की तीय आशोचना की गयी है। फलस्वरूप 1929 ई में शासन हारा मित्रयों की शक्ति सम्बर्धी समिति (Committee on Ministers Powers, 1929) की स्थापना की गयी थी। इसका काय प्रदत्त विधान एव यायिक कार्यों सम्बर्धी मित्रयों की शक्तिया एवं ससदीय एवं विधि की सर्वांच्यता की हथ्टि से आवश्यक सुरक्षा सम्बर्धी सुमार्थी मित्रयों की शक्तिया एवं ससदीय एवं विधि की सर्वांच्यता की हथ्टि से आवश्यक सुरक्षा सम्बर्धी सुभाव देना था।

समिति ने अपने प्रतिवदन में प्रदत्त विधान एवं प्रशासकीय याय की अनिवायता को स्वीकार किया या परन्तु कुछ सुरक्षास्मक सुभाव प्रस्तुत किये थे। समिति
का मत या विद्युद्ध याधिक काय मिं नयों को नहीं सीपे जाने चाहिए अधितु उ हे अद्ध
याधिक प्रकृति के कार्यों को ही करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, विधि के प्रस्त पर
आहत पक्त को उच्च यायात्म (High Court) म अधीन का अधिकार होना चाहिए,
किसी म नी या मिं त्रमण्डलीय अभिकरण को विधिक शक्ति में चौहए तथा प्रशासकीय
म रोकने के अधिकार उच्च यायात्मय को प्रदान किये जाने चाहिए तथा प्रशासकीय
न्यायात्म्यों की कायपदार्वि प्राकृतिक विद्या तो के अनुकृत्व होनी चाहिए। इसके अतिरक्ति सम्बध्धित पक्षों को निष्यों के कारण नात करने का अधिकार होना चाहिए।
निणय के साथ साथ निरोधक की रिपोर मी प्रकाशित होनी चाहिए। समिति नै
प्रशासकीय न्यायात्म्यों के पुनगठन एवं उनके सम बये के सम्बध्य म कोई सुभाव नहीं

दिया या । समिति के संबस्य भी रोवसन ने तो प्रशासकीय पायासया की स्वापना क गुभाव को ही स्वीकार हिं किया। समिति ने व्यक्ता प्रतिवेदन 1932 ई म प्रस्तुत र्षंभाव का हा रवाकार है। १४ था। कामाव प्रथमा जावका । उसके बाद तो प्रशासकीय याय के क्षत्र म बहुत विकास हो चुका है।

1955 इ. म सर बोतिवर फेसस (Sur Olaver Franks) की अध्यक्षता म प्रशासनीय यायाधिकरणो नी कायपद्धति पर प्रतिवेदन देने ना सायित्व एक समिति को सोवा गया। 1957 ई में इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में विश्वार खाक कि थे। समिति के निषय तीन तत्वा पर आधारित है

(1) विधि के सदम में प्रशासकीय यायालयों के सभी निषयों की सभीक्षा का अधिकार सामा य यायालयो को होना चाहिए।

(2) निषय का वायित्व यायाधिकरण (Inbunal) की अपेक्षा यायालयो हो एवं विमाणीय में त्रियों की अपेक्षा यायाधिकरणों को सीया जाना वाहिए।

(3) वायालय द्वारा सुनवाई कं स्थान पर मि त्रमण्डल अथवा यायापिकरण के द्वारा जान के कारण किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों की मुख्या को कोई स्वरा

वक्षेप म समिति का मत वा कि प्रशासकीय यापाधिकरणो को प्रशासकीय हित म काम नहीं करना चाहिए अस्ति की की की विकास के स्वय में काम ्रेश करना वाहिए वास्तु व्याप्त के वादकारा के स्वर क व्याप कार् करता वाहिए। समिति की हिंदि स प्रशासकीय न्यायाधिकरण यक्ति की माना के बारे म निषम करने नाओ एक निष्मक्ष सहया है। समिति ने ट्रेक्से निमम के इस तक को स्त्रोहर नहीं किया कि प्रशासकीय अभिकरण शासता न के अब हीत है जा वे यापिक संस्थाएँ नहीं है। समिति ने अधासकीय व्यासकरण शासनत न भ वा एस ए वा वा विकास स्थाएँ नहीं है। समिति ने अधासकीय व्यामाधिकरणों की कायरवाति के संदेश म जुली जाव सुनवाई एवं निपक्षता एवं ईमानदारी का तुमाव दिया है। समिति क अनुतार इन अभिकरणों के अध्यक्ष को नियुक्ति म नी हारा नहीं की जानी चाहिए अपितु लाड वा सतर को यह अधिकार प्रतान किया जाना चाहिए। हास्य वित पक्षा को मुक्तमें की मुनवाई की सुचना पर्याप्त समय रहते भी जानी चाहिए जित्तमें वह अपना पक्ष प्रस्तुत कर तके। यावाधिकरण द्वारा निषय देते समय उपतन्थ सम्बद्धित साहया एवं कानूनों का जल्लेख करना चाहिए।

फास की तरह बिटेन म प्रशासकीय यायास्त्रों के विकास की सम्मावना कम है। क्रमता परिवतन एवं गुक्तावों द्वारा प्रचासकीय विधि एवं यास व्यवस्या के दोसी को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। आवस्यकता इस वात की है कि प्रवास कीय वामाधिकरणा मं यायिक इंटिकोण का विकास होना चाहिए। यह स्पट एव विनिश्चत कायवद्धति एवं मीलिक विधिकारी के प्रति वास्या से ही सम्बद है।

स्विद्यारत्वण्ड एक संघारमक दस है। संयोग मायपालिना के अतिरिक्त मत्येक रेण्टन की अपनी पुषक पायिक व्यवस्था है। अधिकास पायिक गाय करना के "यायालयो द्वारा सम्पादित किये जाते हैं। कैण्टनो की याय व्यवस्था के अतगत तीन प्रकार के "यायालय है। शिखर पर कैण्टनो के उच्च यायालय (High Courts) हैं उनके नीचे जिला "यायालय (District Courts) एव सबसे नीचे जिल्टिस ऑफ पीस (Justice of Peace) के "यायालय है।

सघोय यायालय (फेडरल टिब्यूनल Federal Tribunal) एकमान राष्ट्रीय यायालय है। अमेरिका की माति स्विट्जरसैण्ड के सधीय यायालय के अघीन क्षेत्रीय तथा जिला सघीय थायालय नहीं होते हैं। लेकिन अपराधिक मामलों के लिए क्षेत्रीय अमणशील सघीय थायालय होते हैं। कैण्टनों के 'यायालयों द्वारा ही सधीय विषया किया किया किया कि ही ही साथीय विषयों के सम्बद्ध वित कैण्टनों के 'यायालयों के निषयों के किया के करत ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है। इस दृष्टि से स्विस याय क्यवस्था एव मारतीय याया व्यवस्था एक सीमा तक साम्य है। अमेरिकी याया क्यवस्था की माति स्वित सथीय 'यायालय के अधीन अपने निणयों को किया वित करते के लिए प्रवक सधीय कमचारी नहीं होते हैं।

स्विटजरलैण्ड मे फास नी तरह प्यक प्रशासकीय यायालय नहीं है यद्यपि सवधानिक सवोशन (1914 ई) द्वारा एक सवीय प्रवासकीय यायालय की स्यापना की गयो पी तया उसे प्रशासकीय वायालय के स्थापना की गयो पी तया उसे प्रशासकीय वायालय के स्थापना के प्रशासकीय मानलों के सम्ब प्रशासकीय किया प्रशासकीय के सम्ब पे ति विच्य करने का अधिकार प्रवान किया गया था। 1925 ई य इस यायालय के वायालय कर वेदाय किया यायालय को सीप दिये गये। अत फास वा पूरोपीय महाद्वीप के अर्थ देशों के प्रशासकीय यायालय की तरह पूपक प्रशासकीय यायालय की तरह पूपक प्रशासकीय यायालय नहीं है। प्रशासकीय यायालय तो वहाँ सवीय यायालय का ही एक कका है। अत प्रशासकीय यायालय ती सामा य यायालया की माति ही एक यायालय है वहाँ सवीय वह सवीय यायालय का प्रशासकीय है। वहाँ सवीय यायालय का प्रशासकीय वायालय है। इस सवीय वह सवीय यायालय का प्रशासकीय है। इस सवीय यायालय की सामा य यायालय की माति ही एक प्रयास है पहुस वह सवीय यायालय द्वारा प्रयुक्त कायपद्वित से प्रिन पद्वित का प्रयोग करता है।

स्विस सधीय "ग्रामानग

स्विस सपीय यायालय का नाम Bundesgenicht है। यायालय का विधान 1874 ई के सविधान में किया गया है। 1848 ई के सविधान में निया गया है। 1848 ई के सविधान में नी एक सपीय यायालय की स्थापना की गयी थी परनु उसे बहुत कम यानियाँ प्राप्त भी एक प्रकार के वह दोकिहीन था। उस परिस्थ एक कैंग्टना की विधियों ता क्षण्या की विधियों के परस्पर विरोधी होने की स्थिति म कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था। यह अधिकार सपीय परिपद (Federal Council) एवं फेडरल अधिकार सम्बर्धी Assembly) को प्राप्त थे। सधीय यायालय होगा नागरिक अधिकार सम्बर्धी विचारों की मुनवाई उसी समय की जा सकती थीं च वर्षिक सधीय परिपद या सधीय समा सपीय न्यायालय को इस सम्बर्धिय करती थी। उस सविधान की

⁷⁸⁶ | आधुनिक शासनतः त्र

व्याख्या करने का अधिकार नहीं या और न संघीय असम्बन्धी द्वारा पारित विधि को वह असर्वेषानिक घोषित ही कर सकता था। वास्तविक अर्थों म वह सर्वोच्च पापालय वहीं था। वह पुणवमा संघोष समयेवी एवं परिवद पर निमर था। यायाधीसा सम्बन्धी ्रेष्ट्रा १ वर्ष दे प्रधान विश्वास के स्वतं के स्वतं प्रधान क भारति का कोई सदस्य या उसके बारा नियुक्त कोई वाधकारी सामाधीस नहीं हो संकता था। असम्बनी तीन वप के लिए यापाधीशा को निवास्ति करती थी। 1874 ई में सिवधान के संशोधन के समय संधीय त्यायालय की प्रक्तियों में परिवतन किय गरें। इतक प्रवात समय तमय पर इतकी सक्तियों में बिंह होती रहीं है 1893 हूं म संयोव यायालय को संविधान दिवालियापन एवं मसासकीय विधि सम्बंधी हुँछ विवादों म सिक्त प्रदान की गयी थी। 1898 ई म संचीय पापालय के दीवामी एव अपराधिक क्षत्राधिकार म विद्य की गयी। सत्य तो यह है कि 1874 ई त्र पुण त्रवयानिक संतीयन के फलस्वकृत संधीय वायात्व की सक्तिया म असाधारण वित हुई है। सी हमा हे जनुसार 1875 ई म बतमान संधीय यायाच्य की स्थापना ्षेत्र हरका अप्रताप क्षेत्र के जोनेक वार वृद्धि मुख्य संधीय परिपद के मूल्य पर होती रही है।

स्विस संघीय यायालय वाण्ड (Vand) नामक कण्टन की राजधानी लुसान (Lausanne) में स्पित है। जुसाने में तथीय यायातव की स्वापना का कारण केंच मापामापी जनता को मावनाओं को संबुध्द करना था। संबंध सासन की अधिकास हस्याओं की स्थापना जमन भाषामापी कृष्टन के बन नगर में की गयी है।

सधीय यायालय का सगठन—सधीय यायालय के यायाधीशा की अहता सम्ब भी कोई अवस्था सविधान में नहीं की गयी है। सविधान में केवल यह कहा प्रमा है कि प्रत्येक नागरिक जो राष्ट्रीय परिषद (National Council) का सहस्य होंने को योग्यता रखता है, सभीय न्यायावय के तिए नियुक्त किया जा सकता है। सरिधात होरा केवल एक यह सत निश्चित की गयी है कि सधीय यामालय के लिए यायाधीस एव उप यायाधीसो को नियुक्त करते समय यह ध्यान म रखा जाय कि परिसय की तीना मायाओं की प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। ¹² संपीय यापालय क यामधीय फेडरल अंतेम्बली हारा 6 वप क लिए निर्वाचित होते हूँ तथा सभीय पायातय का एक अध्यक्ष एव उपाध्यक्ष भी निर्वाचित निया जाता है जिसका काय काल 2 वय होता है। इहें बुर त ही दूसरे सन के लिए पुन निर्वाचित नहीं किया जा तकता। परम्परा या अभिवसय के अनुसार यायाधीय नव तक चाहते हैं पुन

²⁰ Hughes C The Federal Constitution of Suntzerland 1954 p 119 22 Article 107 (1)

निर्वाचित होते रहते है । यद्यपि सविधान द्वारा यायाधीओं के लिए कोई विधिक अहता तिर्धापित तथी की गयी है परात उच्च विधिविज ही यायाधीश नियक्त किये जाते है। "याग्राधीओं की पन निवाचन सम्बन्धी परम्परा एवं व्यवस्था के कारण "याया घोड़ों का कायकाल जीवन भर के लिए स्थायी सा हो गया है, फलत निर्वाचन व्यवस्था से उत्पन्न 'यायाधीको की स्वतन्त्रता के नष्ट होने सम्बाधी मय निर्मल हो गया है। "यायालय के निषयों में कभी कभी राजनीतिक दवाद सलकता है परात इस कारण यायालय पर निष्पक्षता के अन्त का दोवारोपण नहीं किया जा सकता। राजनीतिक दबाव की समान माता की अनुभति तो कभी कभी ब्रिटिश एव सबक्त राज्य अमेरिकी यायालय के सदभ में भी अनभव की जाती है।

स्विस संघीय वायालय के वायाधीओं की सरया 26 है। इसके अतिरिक्त 11 उप या वैकल्पिक यायाघीच (Alternative or Substitutive or Deputy Judges) होते है । 1943 ई के यायिक संगठन विधि (Law on Judicial Orga nisation) के अधीन संघीय यायालय का संगठन निर्धारित किया गया है। इस विधि के अधीन यायाधीशो को अधिकतम सख्या 26 से 28 तक एव वैकरिपक न्यायाधीशा की सरया 11 से 13 तक निश्चित कर दी गयी है।

सधीय "यायालय की शक्तिया एव क्षेत्राधिकार-स्विस सधीय 'यायालयी की दीवानी, अपराधिक, सबैधानिक एव प्रशासकीय विवादो मे मौलिक एव पुनरावेदनीय

क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

(अ) बीवानी क्षेत्राधिकार-परिसच एव कैण्टनो, कैण्टनो के मध्य एव परिसध तया कैंग्टन और कैंग्टनो एव नागरिको के मध्य 4000 फ्रेंक से अधिक मुख्य के दीवानी विवादों में संघीय याथालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। कुछ विशेष प्रकार के नागरिका क पारस्परिक विवादा (यया-राष्ट्रीयता एव नागरिकता सम्बाधी विवाद) म भी यायालय की मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

परिसय को अय विवादों के सम्बन्ध से यायालय के क्षेत्राधिकार को बढाने का अधिकार सविधान द्वारा प्रदान किया गया है (अनुच्छेद 144)। इसके अतिरिक्त व्यापार एव चल सम्पत्ति. ऋण दिवालियापन, कॉपीराइट सरक्षण एव औद्योगिक आविदकारों सम्ब धी सभी विधियों को देश म समान रूप से कियाचित करना संघीय 'यायालय का दायित्व है। कैण्टनो के उच्च न्यायालया के 4 हजार फेंक से अधिक मूल्य के संघीय विवादों के निणयों के विरुद्ध अपील संघीय यायालय म हो सकती है (जन्च्छेद 111)।

(ब) अपराधिक क्षत्राधिकार—संघीय यायालय को निम्न विवादों में फीजदारी या अपराधिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं

(1) परिसम के विरुद्ध देशद्रोह एव समीय अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह एव हिंसा सम्ब धी विवाद ।

- (2) व तर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध व्यवसम् एव अभियोग । (3) राजनीतिक अपराध एव दुराचार के एमें मामले जिनके कारण अव्यवस्या कं व्याप्त होने सं संघीय हस्तदाप वावस्यक हो जाय।
- (4) सघीय उच्च प्राधिकारी (authority) द्वारा नियुक्त किसी अधीनस्य वि निर्मित वि सम्बाधिक समिता यदि समीय प्राधिकारी हारा यायालय ^{के} समक्ष विवार भी प्रस्तुत विया जाता है। प्राप्त है।

यायातव के फीनदारी क्षेत्राधिकार म परिसय की वृद्धि का अधिकार

फीजदारी याय काय के लिए संघीय यायालय की चार कक्षा—संघीय फीजदारी यायालय (Federal Criminal Courts) अमियोग यायालय (Court of Accusation) जुनवाई बायालय (Court of Caussation) एव सुनवाई का सन्त यायानीय असाधारण यायानय (Extraordinary Court of Caussation of Seven Judges) म विमाजित किया गया है। फोनदारी विवादो को निपटाने के निए सघीय यायालय का फोजदारों कहा समय समय पर भ्रमणशीन यामालय के रूप म देश के पाच विभिन के द्वी पर अपने सम्मेलन करता है एव विवादों में निषप देता है। सम्बंधित क्षत्र की जनता हारा जूरी के सदस्या को 6 वप के लिए निर्वाचित किया जाता है। किसी अपराधी व्यक्ति की दण्ड देने के लिए 5/6 जूरियों का समयम आव-रयक होता है।

- (स) सवधानिक क्षेत्राधिकार—संघीय यायालय को निम्न सर्विधानिक मार म क्षेत्राचिकार प्राप्त है
- (1) परिसम एव कण्टनों के अधिकारियों के सध्य क्षेत्राधिकार सम्बद्ध (2) कैंग्टना के मध्य विधि सम्बाधी विवाद।

(3) सम एव कण्टना क सविधाना तथा कण्टना के मध्य सर्विधो या सम-कीता के प्रतस्वहव नागिरक को प्राप्त अधिकारों के अतिक्रमण सम्ब घी विवाद।

परिसम् एव कण्टना के क्षेत्राधिकार सम्बन्धी निवादी में संबीच यावात्वय का यह कतव्य है कि वह कण्टन के सविभान की तुलना म संघीय सविभान एव कण्टना की सामा य विधियो एव जादेखों की तुसना म कच्टना व सविधानों को महत्व एव प्राथमिकता प्रदान करे।

(द) प्रशासकीय क्षेत्रापिकार—1928 ई वे सपीय यायालय को सीमित प्रशासकीय क्षेत्राधिकार प्राप्त हो गया है। उसे सायजनिक विधिकारिया की विधिक क्षमता सम्बंधी विवादा का निषय करने के साथ साथ रतव एवं करा सम्बंधी अनेक विवादों को निषय करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

सधीय दावालय की स्थिति-सधीय देशा की यायपालिका को सामा यत सौपे जान वाला प्रमुख दायित्व सविधान का निवचन स्विस सधीय यायालय को नहीं सौपा गया है और लिखित सविघान वाले देशों में व्यक्तिगतस्वत बता हेत प्रदत्त अनियत्रित यायिक पुनरीक्षण का अधिकार मी प्रदान नही क्या गया है। सयुक्त राज्य अमेरिका एव स्विस सचीय याय-व्यवस्था ने पर्याप्त अत्तर है। स्विस सचीय यायालय राष्ट्रीय यायालय है पर तु सबुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च यायालय की माति इस यायालय के अधीन संघीय अधीनस्थ 'यायालयो की देशव्यापी शृखला नहीं है। स्विस संघीय यायालय को अपने निणया को किया वित करने के लिए कैण्टनो के अधिकारो पर निभर रहना पडता है। दोना यायालया म मध्य भेद तो शक्तिया सम्ब भी है। अमेरिकी सर्वोच्च यायालय को काग्रेस एव राज्यों की विधियों को अवै-धानिक घोषित करने का अधिकार है लेकिन स्विस सधीय 'याग्रालय को इनती व्यापक यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त नहीं है। वह केवल कैण्टनों की विधियों को ही अवैधानिक घोषित कर सकता है। संघीय समा की विधियों के सादम में उस यह शक्ति प्राप्त नहीं है। सविधान द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि संघीय यायालय संघीय सभा द्वारा पारित प्रत्येक विधि को लागू करेगा (अनुच्छेद 113) तथा स्वीकृत प्रत्यक सिंध एवं समभौत को मायता प्रदान करेगा। सविवान की व्याख्या एवं सधीय विधियों के निवचन का अधिकार सधीय सभा को प्रदान किया गया है। अमेरिकी विधिवेत्ताओं को यह स्थिति किसी अवस्था में भी स्वीकाय नहीं हो सकती क्योंकि उनके मतानुसार सविधान द्वारा प्रदत्त शक्तिया का अतिक्रमण विधानमण्डल किसी भी अवस्था में नहीं कर सकता। विधानमण्डल को विधिया के निवचन का अधिकार प्रदान करना अधिकारो का अतिक्रमण करने वाले अधिकारी को स्वय अपने ही मामले मे यायाधाश के दायित्व सीप देने के समान है। अमरिकी सर्वोच्च यायालय को प्रशास-निक अधिकारिया हे सम्बन्धित मामलो में स्विस सधीय "यायालय की जपेक्षा ब्यापक शक्तियाँ प्राप्त है।

स्मरणीय है कि महाद्वीपीय देखों म यायपालिका कायपालिका एवं व्यवस्थापिका के अधीन होती है। स्वित सविधान में इसी मायदा को स्वीकार फिया गया
है। जनमत सग्रह की प्रत्यक्ष प्रवात त्रीय व्यवस्था के कारण स्विट्यरक्षण्ड म यायिक
पुनर्राक्षण की कोई व्यावहारिक उपयोगिता भी नहां है। इसके अतिरिक्त क्लेक मह्यपूण मामले स्वित सधीय न्यायालय के धेनाधिकार में नहीं हैं। उदाहरणाथ, सधीय
कार्यपालिका एव सपीय न्यायालय के मच्य विवादा का निषय सपीय समा करती
है। स्पट है स्वित सधीय न्यायालय को अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की नित्य
त्रपने अधिकार सम्बंधी मामला म निषय की शक्त प्राप्त नहीं है। रेपार निस्ता
सपीय न्यायालय के सदय म कहा है कि सधीय न्यायालय को सधीय नियंवा का
वर्षेध पोषित करने के अधिकार देने का अय एक अस्वन्त कमओर न्यायपालिका

पर ऐसा भार डालना है निसके नारण कभी-कभी अभेरिकी यायपासिका सडसडाती हुई प्रतीत होती है ।22

यायाधीचा की नियुक्ति एव कायकाल तथा यायालय के सगठन की हिन्द से मी त्विस एवं अमेरिकी सर्वोच्च यायात्वया म अंतर है। त्विस यावाचीस समीय विधानमण्डल द्वारा चुने जाते हैं। अमेरिको सर्वाच्च यायालय के यायाधीस राष्ट्र पति हारा सीनेट के अनुमोदन से नियुक्त किये जाते हैं। व्यवहार म मते ही क्विय यायाधीचा का कायकाल जीवनपय त हो पर तु विधिक हिन्द स वे कवल 6 वप के निए ही नियुक्त किय जात हैं। अमेरिकी यायाधीस सदाचरणपयन्त अपने पद पर बासीन रहते हैं। यह स्पष्ट है कि स्विस संघीय पायालय अमरिका एव मारतीय सर्वोच्च यायालय की मीति शक्तिशासी नहीं है। अमेरिका म यायिक प्रधानता को स्वीकार किया गया है जबकि इंगलब्ह म संसदीय सम्मुता की । इसके विपरीत, चिटाजरलण्ड म प्रत्यक्ष प्रजात व वर्षात जन प्रमुख का बिहात माय है। स्विटजर् लिण्ड म यायालय एवं विधानसण्डल के सदम में संसदीय संप्रमुखा को मायला दी गयी है। मारत में यायिक एवं संसदीय प्रधानता के मध्य के माग का अनुसरण किया गया है। जनर का मत है कि दिवस संघीय यायालय को यदि यायिक पुनरीक्षण की चिक्त दे भी दी जाती तो भी अपने सीमत एवं वस्पवस्थित सेनाधिकार के कारण नह संघीय विधियों के पुनर्रोक्षण का प्रमावसाली यत्र वहीं ही सकता या । सकीय म व्यास मा अभाषधाचा न १०० ४० व्यास स्वास महत्व मही है जो अमेरिका एवं मारतीय शासन व्यवस्थाको म इन देशो के सर्वोच्च यायालयो का है

कनाडा सभीय देश है। कनाडा म सभीय एव प्राचीय यायपालिकाएँ हैं, पर तु वे पुषक पायपातिकाएँ नहीं है स्थोकि उनके मध्य विभाजन रखा वस्वाकार न होन्द्र समाना तर (bonzontal) है। संघीय बासन को सामा य पुनरावेदनीय एव अय अतिरिक्त यायालयो की विधि द्वारा स्थापना का अधिकार है। ⁴सधीय यायपालिका 23

To endow it with the right of disavowing Federal statute A of the own it with the right of disayowing rederal statute would therefore be to impose on a much weaker court a much would increde be to impose on a much weaker court a much heavier burden than that under the American Judiciary a much constraint of Scotterland 1936 p. 91 — Rappard, W. F. The

In view of the Tribunal s limited and unsystematic jurisdiction, an view of the 1 fibraria 3 minimum and univariant could hardly serve as an effective instrument of reviewing Rederal festilation judicially even if such a power was inhered in it — Zureher cited by V D Mahajan delect Modern Govern 25 Section 101

में दो यायालय है प्रथम, सर्वोच्च यायालय, और द्वितीय, वित्तीय एव नौ सैनिक याया-लय (Court of Exchequer and Admirality) । इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्राप्त म उच्च जिला एव काउण्टी यायालय होते है। सधीय यायालयो को सघीय विधिया एव प्रातीय विधियो सम्बाधी विवादों को सुनने का अधिकार होता है। प्रातीय उच्च यायालयो का सगठन विभिन्न प्रातो में भिन्न भिन्न है, उदाहरणाय मोबोस्कोशिया म एक उच्च "यायालय है तथा एक एक "यायाधीश स्थान-स्थान पर जाकर उच्च पनरावेदनीय यायालय के रूप में काय करते हैं, औ टोरियों में उच्च यायालय की दो ज्ञालाएँ है--पूनरावेदनीय यायालय (Court of Appeal) एव उच्च यायालय (High Courts) । सभी प्रातीय यायाधीशो को सम्बर्धित मिनगण्डलो की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। वे सदाचरणपय त अपने पद पर काय करते है। 5 उनका वेतन. मत्ता एव पदनिवत्ति वेतन सदन द्वारा निश्चित किये जाते है तथा उनके पदावधि-काल मे उन्हें कम नहीं किया जा सकता।

सर्वोच्च यायालय की स्थापना 1875 ई मे की गयी थी। 1952 ई मे इस चायालय के सगठन, शक्तियो आदि के सम्ब घ मे नवीन विधि पारित की गयी है। सर्वोच्च यायालय म एक मुख्य यायाधीश एव आठ अय वायाधीश होते है। 27 वे के द्रीय मित्रमण्डल के परामश पर गवनर जनरल (राज्याध्यक्ष) द्वारा नियुक्त किये जाते है। सर्वोच्च यायालय का मृत्य कार्यालय औटावा (Ottawa) मे ह। सभी याया-धीश सदाचरणपयात अपने पद पर रहते हैं पर तु 75 वप की आयू पर वे अनिवासत अवकाश ग्रहण कर लेते है। यागाधीशों को ससद के दोना सदनो द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही पदच्युत किया जा सकता है।

सर्वोच्च यायालय को अपीलीय एव परामञ्जदायी क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उसे दीवानी एव अपराधिक दोना ही मामलो म पूनरावेदनीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अप-राधिक मामला मे अपील सर्वोच्च यायालय मे तभी की जा सकती है जबकि प्राप्तीय पुनरावेदनीय यायालय (Court of Appeal of the Province) ने सवसम्मत निणय न दिया हो। सर्वोच्च यायालय का विभिन्न प्रातो क सादम म निम्न पूनरावदनीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। सधीय शासन का विवि द्वारा अपीलीय क्षेत्राधिकार की कम करने या वढान के अधिकार प्राप्त हैं। प्राप्तीय विधानमण्डला को इस सम्बाध में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त निर्वाचन सम्बंधी अपीलों का निणय भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। गवनर जनरल को किसी विधि या घटना के सम्बाध म सर्वोच्च "यायालय से परामश करन का भी अधिकार है। इसके अतिरिक्त कॉम स

²⁶ Section 99

²⁷ प्रारम्म में सर्वोच्च यायालय म कुल 6 यायाधीश ने। 1927 ई म यह सस्या 6 यी परतु 1949 ई म बढकर 8 हो गयी थी।

समा एव सीनेट द्वारा व्यक्तिगत विषेयका को परामस हैतु यदि यायालय को भेजा जाता है तो उ है यायात्म परामश्च देता है। 1933 ई तक अपराधिक मामता की अपोले डमलण्ड की श्रीवी परिपद की यामिक समिति द्वारा सुनी जाती थी। 1939 ई म दोवानी मामला की वर्षाता को इंगलच्छ की प्रोबी परिपद की पाधिक समिति र व वाकाण वाकाण वा जवाण का रेगणक वा नावा वास्त्र वा वाकाण वा ने मेनन वर प्रतिव स लेगा दिया गया है। अतः सर्वोच्च त्यावालय व नाडा का सर्वोच्च संघीय पुनरावदनीय यायालय है। इस यायालय को गायिक पुनरीसम् (Judicial review) की बिक्ति भी प्राप्त है। उस बाबायन मा बावनम उत्तरावान कि कि मी प्राप्त है। संधीय एवं प्राचीय विद्यानमण्डल द्वारा पारित विधिया को जनने सर्विधान विरोधी होने की अवस्था म असवधानिक धोपित करन का अधिकार प्राप्त है। वित्तीय एव नौसनिक यायासय

इस यायालय की स्थापना 1875 ई म सर्वोच्च यायालय के अग क रूप म हुँई थी । 1952 ई म Exchequer Act के अंतमत इस वायात्व की प्रथक माया-लय का स्तर प्रदान किया गया है। इसम एक अध्यक्ष एव पीच यायाधीस होत हैं जो संपरिपद गवनर जनस्त हारा नियुक्त किय जाते हैं। इन यायाधीसा का कामकाल सवाचरणपत्र त होता है परंतु 75 वय को शादु प्राप्त करते पर वे अनिवासत अवकास प्रहेण कर लेते हैं। है व गवनर जनरत हारा कॉम ह समा एव सीनेट के प्रस्ताव पर पदच्युत हिय जा सकते हैं। इस मायानय को काउन के निरुद्ध दायर किसे जाने वाले समी सधीय विषयो सम्ब घी मुकदमो म मीतिक क्षेत्राधिकार तथा नीसेना सम्ब घी विवादों से मौतिक एवं पुनरावेदनीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। पेटेंट कापीराइट, ट्रेंड माक एव भौधोगिक मामना सम्बंधी विवाद भी इसी यायात्वय के क्षेनाधीन हैं। इस याया-लय के विशिष्ट रायित्व हैं अत यह यायासय अमेरिकी संधीय यायासय की मीति का यायालय नहीं है। 500 पीण्ड से अधिक मूल्य के विवास म ही इस यायालय क निवासों के विश्व अपीत सर्वोच्च यामालय म सम्मव है। इसके अतिरिक्त निम्म विवादा म नी इस पायालय के निषयों के विरुद्ध अपील की वा सकती है (1) किसी तिथीय या प्रातीय विश्वेयक की वधना सम्बंधी प्रश्न पर, एवं (2) सासन क विसी पद क सुल्क एवं कत य, किराया, राजस्य वादि विवादों से सम्बद्धित प्रशासनिक निणय । इन विवादो में वापील तभी सम्मव है जब सर्वोच्च यायालय हारा विश्वय अपील (Special leave to Appeal) की बनुमति प्रदान की गयी हो । as scare to (१९४८वा) का जडुकार कार्य कार्य हुए। इताहा की डोमीनियन या वधीय संस्कार को ही सभीय एवं आवीय यावा

लयों के मात्राधीना की निमुक्ति बेतन एवं परच्युति के सम्बंध में निष्यु तेने के अधिकार हैं। ⁹ इसके कुछ ही वयबाद है। इसके अविरिक्त अपराधिक विवादों के 28 Section 99 of the British North America Act 1867

²⁸ Section 99 of the British Porth America Act 180/ 29 Section 92 (14) नोबोकोविया एवं यु व्यक्तिक क Courts of Probate

इम्बाध म पद्धति निधारित नरने का अधिकार डामीनियन झासन को प्राप्त है। क्वाडा का सर्वोच्च यायालय कुछ मामला म ता अमेरिकी सर्वोच्च यायालय से मी अधिक सिक्तालो है। उस विस्कू प्रात्तीय विषया सम्बाधी विवादा म प्रात्तीय यायानत्त्रया न निणया ने विद्ध अधील सुनने का अधिकार है। लेकिन अमेरिकी सर्वोच्च त्यायालय की माति इस यायालय को सविधान ने व्यान्या का अधिकार प्राप्त नहीं है क्याक्त कराडा की सपीय सरकार को प्रात्तीय विषयका को अस्वीकार करने ना अधि कार है तथा अवधिष्ट झक्तियाँ सधीय शासन म निहित हैं। अपात्ति एव आयरिश सर्वोच्च यायालय की मीति ही क्वाडा के सर्वोच्च यायालय की प्राप्त एव आयरिश सर्वोच्च यायालय की प्राप्त ही ही ही क्वाडा के सर्वोच्च यायालय की प्रामश्वायी क्षेषा-

आस्टेलिया की ग्वायपालिका

आस्ट्रेलिया एक सभीय राज्य है। आस्ट्रेलिया की न्यायिक दाक्ति आस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय (High Court of Australia) एवं उन न्य सभीय न्यायालया में निहित है जिनकी समद स्थापना करती है। उच्च यायालय के निर्देश्त दो अ य सभीय न्यायालय हैं (1) सभीय दिवालिया न्यायालय (Federal Court of Bankruptcy)³¹, एवं (2) राज्य का औजीगिक न्यायालय (Commonwealth Indus trial Court)³²। राज्यों की अपनी न्यायपालिका होती है जिनमें विचित्र न्यायालय हैं। इनक न्यायाभीशा को राज्यों के यवनरों हारा नियक्त क्या जाता है।

जास्ट्रेलिया का उच्च यावालय संघीय याय व्यवस्था का सर्वाच्च यायालय है। मिनयी के परामद्य पर यननर जनरल द्वारा इसके यावाधीशो को नियुक्त किया जाता है। उनका कारकाल सदाचरणप्य तहोता है। इस समय उच्च यावालय में एक मुत्य यावाधीश एवं 6 ज्य यावाधीश है। दुराचार का आरोप प्रमाणित होने पर तथा मुत्य यावाधीश एवं 6 ज्य यावाधीश है। दुराचार का आरोप प्रमाणित होने पर तथा सकत के बोना सदनो द्वारा एक ही सज्य से तत्स्वय धी प्रस्ताव पानित करने पर गवनर सनर स्वायाधीशों का उनके वेतन एवं वाय मत्तों को उनके कोन सहन हो है। उनके वेतन एवं वाय मत्तों को उनके कोनकाल म इस प्रकार कम नहीं किया जा सकता है कि उन्ह हानि पहुँचे। निम्नलिखित विवादा से उच्च यावालय को मीलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है

किसी सिंघ अथवा अ य देशा के प्रतिनिधियो एव म ती से सम्बिधत विवाद, राज्यों के मध्य या विमित्र राज्यों के नागरिकों के मध्य या एक राज्य एव अ य राज्य के नागरिकों के मध्य विवाद, व सभी विवाद जिनमें के दीय शासन एक पक्ष में हो तथा के द्रीय राज्याधिकारी के विरक्ष यायालय से निषेषाना की माम की सयी हो.

³⁰ Strong Modern Political Constitutions of cit p 122

³¹ यह यायालय समस्त दिवालिया सम्पत्ति सम्ब धी विवादा पर निणय देता है।

³² यह प्रमुख औद्योगिक विवादा सम्बाधी थायालय है।

³³ Section 75

ब दी प्रत्यक्षीकरण तथा परमादेश (Mandamus) सम्ब भी लेख (writs) सम्ब भी विवाद, संविधान एवं उसकी व्याच्या सन्वधी सभी विवादा तथा प्रधासकीय गासा-विकरणा के निषया के विरुद्ध वयीला को निश्चित बरन के सम्बन्ध म उड़ब यासस्य को मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

इसके अतिरिक्त उच्च यायालय को सभी सधीय न्यायालया क निणया एव अपने एस निषया एवं आदेशा तथा दण्ड जिनका सम्य घ मौतिक क्षेत्राधिकार ते होता है के विरुद्ध अपील सुनन का अधिकार है। इसके अतिरिक्त अप पायालया हारा जो संघीय संगाधिकार के अधीन हो, राज्य के उच्च यायासय या जय कियी राज्य क यायालय या अंत राज्यीय आयोगा के निणयों के विरुद्ध अपीत उच्च यायालय म की जाती हैं यदि उन विवादी म विधि का बोद प्रकन निहित होता है। ऐस समस्त विवादा म उच्च यायाखय का निषय अतिम एव निर्णयक होता है। संसंप म, उच्च यायालय राज्य के यायालयों का सामान्य पुनराबदनीय पायालय हैं। केवल छोटे विवादा की अपील वहाँ नहीं ही सकती हैं।

बास्ट्र्लिया की सघीय ससद (कामनवेत्य की ससद) को उच्च यायासय के मौतिक सेनापिकार में विधि होरा विद्वि का अधिकार है। सविधान संसदीय प्रति-निधिरव, मो क्षेमा, जलीय यातायात सम्बन्धी विवादो एव ऐसे सभी विषया म (जिनसे तम्ब धतं विभिन्न राज्या में भिन मिस विधियाँ प्रचलित हैं) के बारे में उच्च याया लय को नवीन मौलिक क्षेत्राधिकार प्रदान कर सकती है।

उच्च यायालय को सबधानिक प्रस्ता के निषय का एकधिकार प्राप्त है एव राज्यों के यायालयों एवं भीवी परिषद की तुलना में संवधानिक प्रक्तों के बारे म उन्ह यायालय की स्थिति विशिष्ट है। यद्यपि राज्या की यायपालिका की समीय भेताधिकार एवं सविद्यान तथा उसकी व्याख्या से सम्बद्धित विवादों की सुनने का अधिकार है परतु जन्म यायासय ऐसे निवासों को राज्य क यायासयों से अपने तमक्ष मेंगाकर त्वय निषय कर सकता है। के द्वे एवं राज्यों के मध्य शक्तियां के विमाजन सम्बंधी मामले म राज्य की यायपालिका की कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इतके अतिरिक्त सिवधान की धारा 74 के वधीन सवधानिक प्रकार के मामले म स्वय यामालय के निषय के निष्य के निष्य के निष्य के निष्य के विरुद्ध अपील उच्च यामालय की विश्वेष अनुसति के बिना नहीं हो सकती है। ऐसा अवसर भी केवल एक ही बार आया है जबकि उच्च याया त्य होरा इस प्रकार की अनुमति प्रदान की गयी है। आस्ट्रेलिया में यह मायता है कि सर्वधानिक प्रस्त आस्ट्रेलिया में ही तय होना चाहिए। बत केड एवं राज्या के होताचिकार सम्याची विवादो म उच्च यायासय सर्वोच्च यायामिकरण है।

भारतीयम् का उच्च यायासय समेरिकी सर्वोच्च यायासय को माति ही सिवधान का सरक्षक है। स्ट्रॉन कं अनुसार, बास्ट्रिवया की संधीय यायपातिका के पाववार का वास्ताक है। स्कृत्य के जाति ही सैविमान की व्याख्या एवं राज्यास्त्रक रूप

इसके अतिरिक्त आस्ट्रेलिया में अमेरिकी संघीय याय व्यवस्था जसी व्यापक प्रामालया की श्रुवला नहीं है। आस्ट्रेलिया में राज्य 'पायालय ही संघीप विवादों के निष्णय करते हैं। प्रत्येक राज्य को अपनी पृषक यायपालिका है। आस्ट्रेलिया की मधीय तथा राज्यीय पाय व्यवस्था के छीप पर प्रीवी परिषद की यायिक समिति है। राज्यों के क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवादों की अपीले राज्यों के उच्च यायालयों से प्रीवी परिषद में की जा सक्ती है।

आयरलैण्ड (आयरिश स्वतन्त्र गणराज्य) की न्यायपालिका

आयरिश गणत तीय सविधान में सावधानक न्यायालयों द्वारा यांग के सम्मा दन की व्यवस्था है। द्वासन के परामक्ष पर त्यायाधीशों की नियुक्ति राज्द्रपति द्वारा की जाती है। सभी त्यायाधीशों को काय सम्मादन म पूण स्वतत्त्रता प्राप्त है। उनका वेतन जनके कायकाल के मध्य में कम नहीं किया जा सकता और दुराबार एवं त्याये ग्यता के अतिरिक्त अत्य किसी कारण यायाधीश को पदच्युत नहीं किया जा सकता। यह तभी सन्मव है जबकि ससद के शेनो सदनो द्वारा तत्सम्बाधी प्रस्ताव पारित

आमरलण्ड का सर्वांच्य यायालय सर्वोंच्य यायिक निकाय है। इसमें एक मुख्य गायाधीश एव चार अन्य यायाधीश होते है। इस मीलिक एव पुनरावेदनीय, दानों ही प्रचार के क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसके अितरिक्त सर्वोंच्य यायालय राष्ट्रपति वो संवधानिक प्रकार पर परामश प्रदान करता है। उच्च यायालय (High Court) के निजया के विरुद्ध अपील सर्वोंच्य यायालय म सुनी जाती है। क्षेत्रोय यायालय के केवल उन्हीं निजयों के विरुद्ध अपील सर्वोंच्य यायालय म की जा सकती है जिनम विधि स कोई प्रका निहित होता है।

आमरिश यायिक संगठन के शीप पर सर्वाच्च वायालय है। उसके नीचे उच्च वायालय (High Court), फौजदारी पुनरावेदनीय वायालय (Court of Criminal Appeal) एवं खनीय तथा जिला वायालय होते हैं।

³⁴ Strong op at , p 118

³⁵ Ibid

बच्च यायालय का दौरानी एव फौजदारी (अपराधिन) दाना ही विवादा म मौलिक क्षत्रायिकार प्राप्त है। विसी विधि की विधानिकता व परीक्षण का इस यावा लय को मौतिक क्षत्राधिकार होता है। क्षत्रीय यापालया क निणया क विरुद्ध अपीते उच्च यायाल्य म मुनो जातो है। इसका एक अध्यक्ष होता है वा सर्वोच्च यायाल्य का पदन सदस्य होता है। इसन अतिरिक्त 6 अय यायाधीस होते हैं। क्षीजवारी पुनरा वेबनीय वायालय म छन् मुख्य यायाधीस या सर्वोच्च पायासम् ४०० ए जानाभार ३०० तया उच्च यायालय क हो यायाधीत होत हैं। सावजनिक विधि स सम्बर्धिय मामला को छोडकर गय सभी मामला म इस यापालय के निगय अन्तिम होते हैं। सावजनिक विधि तस्व यो विवादों की अधोत सर्वोडक यावासय म की जाती हैं। संत्रीय ए-जिला यायालय स्थानीय अदालत हैं एव जनक धनाधिकार भी सीमित होत हैं।

नवीन सविधान के पूर्व जापानी याय व्यवस्था पर जमन याय व्यवस्था का प्रमाव था। यायपालिका स्वतंत्र बही थी। वह कायपालिका का एक अगमात्र थी। लिकन नवीन सिवधान म मामपातिका की स्वत त्रता क सिवान्त की मा यता दी गयी है। देश की समूच यायिक सत्ता सर्वोच्च यायास्य एवं विधि द्वारा स्थापित क्षय अधीनस्य यायालया म निहित है। किसी अय विशिष्ट यायालय को स्थापना नही की जा सकती और सबिधान क अनुसार अतिम रूप म यायिक सत्ता किसी काय-पालिका अभिकरण को नहीं दी जा सकती है।

सर्वोच्च मायानय म एक मुख्य वायाधीय होता है तथा अय यायाधीसा की संस्या तसद का विधि द्वारा निश्चित करने का अधिवार प्राप्त है। ससदीय विधि क अनुसार सर्वोच्च यायासय में एक मुख्य यायाधीस तथा 14 अस यायाधीस हैं। इतम 10 यायाधीस उच्च विधिक योग्यता के वाधार पर चुने जाते हैं तथा स्थ यायाभीको का विभिन्न क्षेत्रों म हे निर्वाचित किया वा सकता है। मुख्य यायाभीक्ष क अतिरिक्त रीय सभी सावाधीश मिनमण्डल द्वारा नियुक्त किये जात हैं। संविधान क भारत स्था वका वावावाल का कार्याल कार्या अस्त है। विश्व कार्या भारत है। वाववार के सिए हीने वाले प्रथम निर्वाचन के समय उनकी निर्मुक्त की समीक्षा जनता द्वारा की जाती है एवं प्रति 10 वप क्षी अवधिक समाप्त होने परप्रतिनिधिसागार के निर्वाचन के समय जनता द्वारा याया भीशा के काय की समीक्षा की व्यवस्था है। यदि बनता बहुमत द्वारा किसी यागा भाषा र राज का चमाला का ज्यारा १ है तो उसे पदच्युत किया वा सकता वाच भा उद्युष्ट पर व हुटाए भा वनानन भूज्या हु जा उद्यु निवस्त का जन्म का जन्म है 1³¹ समीक्षा क सम्बन्ध म जापानी डाइट (ससद) को व्यापक विविधा बनाने का

³⁶ Refer to Chapter VI of the Japanese Constitution Articles 37 Article 79

अधिकार प्रदान किया गया है। ससद नो पदिनिवृत्ति सम्ब थी आयु सीमा निर्यारित करने का अधिकार दिया गया है। ससदीय विधि द्वारा यह आयु 70 वय निश्चित की गयी है। सर्वोच्य प्राधात्मय क प्राधाधीता का वक्त एव मत्ता जनक काम-काल के दौरान कम नहीं किया जा सकता है। कायपालिका या उसक किसी अनिकरण या अग को प्राधापीता के विकद्ध अनुतासन सम्ब थी कोई कामवाही करन का अधिरार प्राप्त नहीं है। सर्वोच्य प्राप्ताय क प्राधापीतों को सावजनिव महासियोंग वे आधार पर पद से प्रयक्त रिया जा सकता है।

मर्वोच्च न्यायालय जापानी याय व्यवस्था के खिलर पर अधिरित है। इसे केवल पुनरावेवनीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा यह 'वायानय विधि सम्बन्धी अपीला की सुनवाई करता है। इसे विधि, लादेज, नियम एव लासकीय नार्यों की वैधानिक्ता की सम्बन्धी माण्य देन का अधिकार है। 18 सविधान सर्वोच्च विधि है तथा राज्य की विधियों, अधिनायमां, साम्रामोध आजाओं एवं लासक के अनेक अया कार्यों को जी सविधान की किसी धारा के विपरीत होत हैं, सर्वोच्च यायात्रय को उन्हें अवधानक घासित करने का अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च यायात्रय अधिवक्तां तथात्रात्रय के विधान की किसी धारा के विपरीत होत हैं, सर्वोच्च यायात्रय की प्रत्यात्रय को उन्हें अधान का विधान की निमुश्चित सिन्यच्छा सर्वाच्च यायात्रय है। 18 अधीनस्य अदालता के यायाधीया की निमुश्चित सिन्यच्छा सर्वाच्च यायात्रय बारा को गयी स्थामाधीधी की सुनी ये करता है। ये से सर्वा है। उन्हें समुचित पारिश्विम दिये जान की व्यवस्था है और वह उनके कायकाल के वीरान कम नहीं क्षिया जा सकत है। उन्हें समुचित पारिश्वमिक दिये जान की व्यवस्था है और वह उनके कायकाल के वीरान कम नहीं क्षिया जा सकता। 19 स्वप्ट है, जापान य यायपालिका की स्वत रता की मायता दी सभी है। ग्रिटा की भीति ही जापान य यायपालिका की स्वत रता की प्राप्त दी स्वा के जनुगमन विध्य प्राप्त है। विद्यात का जनुगमन विध्य प्राप्त है। विद्यात का जनुगमन विध्य प्राप्त है।

सर्वाच्च 'यायालय के अधीन ब्राष्ट उच्च त्यायालय है। सम्पूच जावान की आठ
प्रधान यायिक क्षेत्रों म विभाजित किया गया है। इन वायालया नो अधिकाशत
पुनरावेकीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अधिकाश मामली म इनके निजय अतिम होते
हैं। उच्च 'यायालयो के अधीन 50 जिला यायालय हैं। इक्के अतिरिक्त जायाल में
निम्न पायालय एवं घरेलू पायालय (Summary Courts and Domestic
Courts) नामक अधीनस्य खदालते भी हैं।

समीक्षा---नवीन जापानी भविधान की 'यायिक व्यवस्था परम्परागत जापानी व्यवस्था के ठीक विपरीत है। फलस्वरूप 'यायालय जायपालिका की माति अपना

³⁸ Article 81

³⁹ Article 77 40 Article 80

काय करते हैं। नवीन व्यवस्था का आधार औरत अमरिनो यापिक व्यवस्था है जिसम यायिक पुनर्रोक्षण का विचार अतिनिहित है। यह विद्वान जापान म हजारो वर्षो स प्रचित्र क प्रमुखियन नितन व राजनीतिक परम्पराज्ञा के प्रतिकृत है। सर्वोत्त यायास्य संवधानिवता सन्व भी निषय दन वाता सर्वोच्च यायास्य है। बत जापान वावाच्य प्रवचानम् । एक्य वा एक्य का व्यवा प्रवच्य वावाच्य वा व्यव्यव्य वा व्यव्यव्य वा व्यव्यव्य वा व्यव्यव्य व मा सर्वोच्च यायास्य अमरिको सर्वोच्च यायास्य वो माति ही यायिक पुनरसिव की विचा स बुक्त है। परंतु अनुच्छेद ४। म इसके विचरीत स्थवस्या है। अनुच्छर वार्या । उत्तर है। इस वार्या विकास का में स्वाप्त का स्वाप्त का कि । इस वार्या का स्वाप्त का स्वाप अय है जापान म त्रिटिस संसद की मीति ही संसदीय सर्वोच्चता का सिंद्रा त मा गई। अत वावालय उसके हारा पारित विधि की संबोधा नहीं कर सकता। विकार हुसरी तरफ तर्वाच्च यायालय को राजकीय विधि, बादस, नियम एव कार्यों की वसानिकता सम्बधी निणय हने बाला अतिम अधिकृत पायालय बहुत गया है। यह दोनो यव स्थाए वरस्वर विरोधी हैं। यह विरोध जापान की यायपालिका के जीवन म स्पटन दिटिगोचर होता है। लेबिन जापानी यायपातिका नागरिक अधिकारा एव सुविन थाओं को रक्षा करने म पर्याप्त सजय एवं सफल है। बाइट क सं रम में सर्वोच्च यायालय को स्थिति वडी नाजुक है। सम्मवत इसी कारण जापानी सर्वाच्च याया लय ने यायिक पुनरीक्षण की सक्ति का प्रयोग नहीं किया है और किसी सासकीय नियम आदेश कायबाही एवं विधि को अवध योपित नहीं किया है। संसदीय सर्वे च्चता एव यायिक वुनरीक्षण के सिदान्त परस्पर विरोधी है। एक साय रोगो कं ध्यवस्या जापानी सविधान का एक विरोधामास हैं। यदि भविद्य में जापानी सर्वोच्च पायात्तय यायिक पुनरींतण की शक्ति का श्योग करता है तो ससद एवं याय पालका म वधानिक सकट उत्पन हो सकता है। फाम्स की त्याय व्यवस्था

- फास की याय 'पवस्यां की मुख्य विश्वपताएँ निम्नवत है (1) फात में दो प्रकार के यायालय है—प्रशासकीय यायालय एव सामाय यायालय। प्रशासकीय यायासयो में शासन से सम्बच्चित विवादो के निजय किये जात है। सामा य यायालयों म सामा य जनता स सम्बन्धित दीवानी एव फीव दारी मामला क निणय होते हैं।
- (2) सामा य यायालयो म विवादों के निषय तीन यायाधीओं की एक पीठ हारा किये जाते हैं वयोकि एक यायाधीश के सरस्ततापूचन प्रमानित होने की थाशका रहती है।
- (3) फ़ास में यायाधीयों को समुचित पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है फलत यायपालिका की तरफ श्रेष्ठ एव बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होते हैं।ध · 41 Ibid, p 228

(4) फास की विधि सहिताबढ़ है। विभिन्न सहिताजो क अनुच्छेद यायिक निणय के आधार होते है। इगलैण्ड की माति फास म कॉमन लॉ जैसी काई विधि नहीं है। अपितु फास म एक भी एसी विधि नहीं है जो सहिताबढ़ न हो।

सिंहताबद्ध विधि (code law) एव कैस लॉ (case law) पर आधारित निषयों म आधारभूत अतर होता है। आग्ल-वेनसन देशों म नजीरा (precedents) पर विशेष वल दिया जाता है पर तु फ़ास से यायाधीश प्रत्यक मामले के अनुसार स्वतः पीत सं विधानमण्डल द्वारा निर्मित विधि के अनुसार निणय देत हैं। इसी-लिए पूमन ने कहा है कि फ़ास के पायिक निणयों म सामाजिक एव आर्थिक परिवतन सहज हो परिसक्तित नहीं होते है। तस्तम्ब ची परिवतन पायालय द्वारा न होतर विधानमण्डल द्वारा किय जाते है। अत कॉमन लॉ पढ़ित की अपक्षा फ़ेच प्रणाली कहीं अधिक कठार है।

- (5) फास म यायाधीश सावजनिक हिलो के रक्षाय सदव तत्पर रहत हैं फलत अपराधी दण्ड के बिना वच नहीं सकता है। इनलैण्ड म प्रचलित इस मायता म उनका विश्वास नहीं है कि 99 अपराधिया का मुक्त करने म कोई दाप नहीं है परतु नहीं ऐसा न हा कि काई निर्दोप व्यक्ति दिण्डत हो जाय । किनु इसना यह मी अय नहीं है कि फेंच यायाधीश अपराधिया को दिण्डत करने के लिए तत्पर रहते है।
- (6) फास म यावाघीता का चुनाव ब्रिटिस याव-प्रणाली से मिन तरह स
 होता है। व इसलैंच्य एव मारत में यावाघीरा वकील वस म स चुन जात हैं। मारत
 म निम्म यावाघित्वा के यावाघीरा का चयन लोक-सेवा आयास करता है। ता
 म निम्म यावाघित्वा के यावाघीरा का चयन लोक-सेवा आयास करता है। ता
 मासीकी अपने जीवन क प्रारम्भिककाल म यावाधीरा होन ता निश्चय करता है। ता
 मतिवोगी परीक्षा म माग लेत हैं वे उपगुक्त पाय जान पर यावपातिका क लिए चुन
 लिय जात हैं। उनके परचात वे एक क परचात हुसरे उच्च न्यायिक पदा मा पदी
 मृति हारा प्राप्त करत चले जाते हैं। फेंच यावाधीश्वा का ब्रिटिस या मारतीय यावा-धीरा ही मीति स्तत प्रता प्राप्त नहीं हाती। उसका कारण यह है कि य यावमृत्रालय के अधिरारी होते हैं तथा यावाधीश्वा की सर्वोच्च परिपर (Supreme
 Council of Magistrature) हारा उनकी निमुक्त एव पदीप्रति को जाती है। कारर
 पूच के ना मन इसत निम्म है। उनके अनुसार सर्वाच्च परिपर क सरस्य। म राज्ञ
 नीतिक एव विधिन यायता क तथान सरस्य हान है। 6 तरस्य राष्ट्रीय असम्बाद्धी
 हारा चुन जात है और 4 पर्येवर यावाधीश हाते हैं। दो महस्या का राष्ट्रपति हारा
 प्रचन जात है। इसन अविरिक्त राष्ट्रपति एव न्यायम प्रो मा परिपर क मरस्य

⁴² Carter Ranney and Hertz The Government of Trurce, p 220

⁴³ Ibid , p 224

800 | आधुनिक शासनतः त्र

होते हैं। अव इस वात को हर मम्मावना है कि सर्वोच्च परिपद स्तीय हिस्कोण है विचार करे। परतु सर्वाच्च वरिषद व जो प्रथम निवृत्तियों की थी जनम उसने माम यायाधीसों को ही निष्ठुक्त किया था। अतः सर्वोच्च परिषद कासीसी यायपानिका की स्वत मता का एक सबस समय त्रमाणित हो सका के 16 तवीय गणराज्य म गाया प्रथा नथा पा एक प्रथम प्रथम निवास है। प्रथम है। प्रथम न्यू प्रथम प्रथम है। प्रथम न्यू प्रथम ने प्रथम में हैं से की जाती सी। चुतुस गमत में प्रसिक्षण स सर्वोच्च परिषद की व्यवस्था की गयी थी। क्षात म अनेक प्रकार क विश्वय प्राणालय है यथा— यापारिक यापाधिकरण, औद्योगिक विकास परिवर्द (Industrial Disputes ९ पराः भागाप्त पामाध्य एमः मध्यापक एकः। पापप (स्थापकार्याः स्टान्स्यः स्टान्स्यः स्टान्स्यः स्टान्स्यः स्टान्स Councils) आदि । इतं अदालवां हः सदस्य पामाधीय मही होते । यह पामालय पच फतना एवं समक्रीता करात हैं निषय नहीं देते। फास के वावालयां का सगठन

फास म दो प्रकार के यायालय होते हैं—सामा य यायालयो ना सगडन सरह एव एकी रूत है। सबस छोटे यायालय Justice of Peace के यायालय कहनाते हैं। इनको साधारण दीवानी एव फोजवारी विवादो में क्षताधिकार प्राप्त है। कुछ नामको म इनका निषय अतिम होता है और बुख निषयों क विश्व अपील की या सकती है। द्वितीय श्रेणी क यायालयों को करेक्शनल कोट (Correctional Courts) कहते है। इनको बुख अधिक महत्वपूष कौनदारी मामला म क्षनाधिकार प्राप्त होता है। इन पायालयो म तीन यायाधीस होते हैं। दीवानी मामनो से सम्बद्धित प्रारम्भिक याया लयों को Tribunal of Fust Instanco कहते हैं। इन अवासतों को बीबोगिक विकास परिपदा एवं Juges de paix की अपील सुनने का अधिकार होता है। इनको मोलिन एव पुजरावेवनीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इन यायालया के दीवानी सामनो सम्ब धं रेंग उर्धानकार कार्माककार कार्म है । निष्यों की अपील अपीलीय अवालता (Court of Appeal) एवं फीजदारी मामती के निषयों की अपीलें अमण्डील यायालयों (Court of Assizes) म की जाती हैं। भाषा का जपाल क्रमणधाल भागाता । इन बोनो अदालता को मीलिक एवं पुनरावेदनीय दोनाधिकार प्राप्त हैं। कास म 27 अपीलीय यायालय है। प्रत्येक हिपाटमा (कास का जिला) म एक अमणधीन म बा भारता है। प्रति तीन माह में इन वायासयों का एक अधिनश्चन विपटिमा क पाधानम् दावा है। जमण्योतः यायावयो एव पुनरावदनीय पायावयो के कार्यो पुरुष क्षत्र में 8(त) है। अभूमधाप पायापार देन उत्तरान्याप पायापार के भाग में अतर होता है ने कि उनके सामाधीसा से 18 अपने भी अब किसी संपत्तिय पायालय के मुस्यालय के नगर में यायालयों के अधिवेशन होते हैं तो। पुनरावेस्तीय पायालय के वावाधीस ही प्रमणशील पायालय के वावाधीसी के रूप म काय करते हैं । दुनरानेदमीय या अपीतीय यायातय म पाच यायाचीस होते हैं एव भ्रमणसीत 44 Ibid pp 224 225 45 Ibid, pp 230 231

⁴⁶ Ibid , p 235

न्यायालया म तीन 'यायाधीश एव अध्यक्ष होता है। व्यापारिक' यायाधिकरणो के निजयो के विषद्ध अपीले पूनरावेदनीय 'यायालयो मे होती है।

सबसे शीप पर Court of Cessation है। यह सर्वोच्च पुनरावेदनीय "यायालय है। वास्तव में यह पुनरावेदनीय "यायालय न होकर सर्वोधन "यायालय (Court of Revision) है। " इसका काय पुनरावेदनीय एव भ्रमणशील "यायालया के निणयों की विधि सम्ब घी प्रस्त के आधार पर समीक्षा के पश्चात उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करना है। यह अस्य त ही व्यस्त "यायालय है। फलस्वरूप विवाद की तब होने में इस "यायालय में वर्षों लग जाते हैं। प्रोब्यूरेटर जनरम, जो अभियोग शाखा ना प्रमुख होता है, किसी भी विवाद में विधि सम्बन्धी प्रस्त पर "यायालय का ध्यान आकर्षित कर सकता है। यह "यायालय केवल विधि सम्बन्धी तकों को सुनता है। इमके तीन विभाग हैं आवेदन (Petition), हीवानी (Civil) एव फीजदारी (Criminal) विभाग हैं अपदेक विभाग म 16 यायाथिश होते हैं।

पचम गणत'त मे भ्यायपालिका

फास के पाचवे गणत त्रीय सिवधान की यायिक व्यवस्था में निम्न दो सस्याओं की और व्यवस्था की गयी है

- (1) "यापपालिका की उच्च परिषव (High Council of Judiciary)— फास का राष्ट्रपति इस परिषद का अध्यक्ष होता है तथा ग्याय मंत्री परिषद का पदेन उपाच्यक्ष हैं। याय-मंत्री राष्ट्रपति के स्थान पर इस परिषद की अध्यक्षता कर सकता है। इसके अतिरिक्त परिषद में राष्ट्रपति हारा नियुक्त नो अन्य सदस्य होते हैं। इस परिषद का अध्य पुत्ररावेदनीय ग्यायालय एव Court of Cessation के न्यायाधीशा के नाम प्रस्तावित करना है। अन्य न्यायाधीशा के सन्धर्म में न्याय मंत्री हारा प्रस्ता-वित नामों पर यह परिषद अपना मत व्यक्त करती है। क्षमाशन के सम्बन्ध में परिषद का परामश लेना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त परिषद न्यायाधीशों के विषद अनुसासनारमक कायशहों भी करती है। परिषद फेंच राष्ट्रपति को न्यायिक सत्ता की स्वत कता की अक्षण्ण रखते में सहसीय देती है (अनुस्केट्स 54)।
- (11) उच्च पायालय (High Court of Justice)—एक उच्च पायालय की भी व्यवस्था की भयी है। हर निर्वाचन या आद्यिक निर्वाचन के पश्चात राष्ट्रीय समा एव सीनेट समान सच्या भ इस पायालय के सदस्या को निर्वाचित करती है। समा एव सीनेट समान सच्या भ इस पायालय के सदस्या हा। क्षेत्र प्राप्त पायालय की निर्वाच सदना हारा राष्ट्रपति पर जन्म पायालय को निर्णय का अधिकार है। यह एक प्रकार से राजनीतिक न्यायाधिकरण है।

प्रशासकीय "यायालय

फास के प्रशासकीय यायालया का संगठन सरल है। 1926 ई के पूर्व प्रति

⁴⁷ Carter etc op est, p 235

हिपाटमा (जिला) म एक प्रचासकीय यायासय होता था। लेकिन प्रत्यक जिला प्रर वित्राच्या (प्रमान) क्षेत्राच्या के व्यापक क्षेत्राच्या के व्यापक क्षेत्राच के व्यापक क्षेत्र के व्यापक के व्यापक क्षेत्र के व्यापक क्र जिला ओफ्नेब्रस्त वरिपदो (Inter Departmental Prefectural Councils) क ्यापना की गयी है। यह प्रारम्भिक भ्रमासकीय न्यापालय है। इनका समाधिकार सीमित है। इनका सम्य ष कैवल स्थानीय अधिकारियों के कार्यों या आहेशों से होता है। पेरिस जिल को एक पुषक परिपद होती है। इसके अविरिक्त 22 अप परि-पद है। मरोक परिषद म एक अध्यक्ष एवं तीन या चार सदस्य होते हैं। इन परिपदी का 90% काय स्थानीय कर निर्धारण से सन्यधित होता है। इसके अतिरिक्त साव-जिनक राजमावों आदि पर पटित होने वाली घटनाओं की बुनवाई भी हही याया लया म होती है।

राज्य परिषद (Council of State) सर्वोच्च प्रशासकीय यायालय है। अत जिला प्रशासकीय पायातयो है निषयो के निष्ठ अपील राज्य परिपद द्वारा सुनी जाती है। राज्य परिपद से विधियो एव अध्यादेशों के प्रारूप तैपार करने में शण्य परामच करता है। यह एक महत्वपूष याविक तस्या मी है। धराज्य परिपद काय दो विमागो म विमाजित है। मुकदमो सम्बंधी शासा (Litigation Sectio) प्रशासकीय मामलो से सम्बचित होती है। इस काय को 30 बरिष्ठ अधिकारियो व परिपद करती है। एक बीधाई सदस्य जिलों से अध्यक्षों (Prefects) तथा दो तिहा। सदस्य परिपदों के कनिष्ठ सदस्यों य स पदोन्नति की रीति से चुने वाते हैं। परिपद क गठन की उपरोक्त रीति के कारण उसके सदस्यों म प्रशासकीय अनुसब प्राप्त अधि-कारियो एवं याधिव योग्यता से सम्पन्न यायाधीशों का सम वस है। मुकदमों सम्बन्धी धाला के अत्यधिक कायमार के कारण उसे कई उप विमानों में विमालित कर दिया गया है।

, प्रत्येक व्यक्ति को राज्य परिषद में सिकायत करने का अधिकार हैं। सिकायत भरत के कई आधार हो सकते हैं, शक्ति का उत्पयोग एवं शक्ति का अत्यधिक भरत क कह बाबार हा चक्का है। राज्य परिवर को भीतिक एवं पुनरावदनीय दोनों ही प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। देवचर के भाषक १७ उर्पण्याच प्राप्त है। इसके निषयों में अव्यक्ति विवस्त होता है, से न्युवार् भारतम् भू ५० ९८ चात्र १ चान्याः भू भागतम् भू विक्र विवादः म सम् जाना सामारख बात है 🎒 इसके विपरीत, काटर एव रेने राज्य परिवद को अनेक कारणों से सावजनिक हिंवों का त्रमावसाली सरसक पुत्र को कायप्रवित्त कम सर्वोत्ती एवं सस्त है। उच्च विकास्यो के निरुद्ध निषय देने म परिषद ने सकीच नहीं किया है। इसके अविरिक्त परिषद ने 48 Carter etc op cut, p 242

⁴⁹ M Duverger The French Political System, p 160

कुछ प्रमुख देशों की यायपालियाएँ | 803

उदारतापुवक व्यक्तियां को श्रांतपूर्वि दिलायी है। प्रश्वासकीय प्यायालय फास भ अत्य-पिक लोकप्रिय हैं। प्रशासकीय निरदुशता पर प्रशासकीय यायालय सुनिश्चित अव-भग भागान्त्र ए । त्रवाराभाव १८५५ अथा १८ त्रवाराभाव प्रवासी व्यक्तियों के हितो का नोवक का काय करते हैं। व्यवहार से प्रशासकीय याय प्रवासी व्यक्तियों के हितो का रसा कवन एव अधिकारिया की नीतकता का सरसक प्रमाणित हुई है। कार में याधिक पुनरीक्षण की व्यवस्था का अभाव है। पाँचवें फेच गण-

तार्था न पार्था अस्ति सर्वेषानिक वरिषद की व्यवस्था है (अनुरुद्ध 5 से 63 तक)। सबमानिक परिपद को सावमवी विधि (organic laws) एवं अस विधिया की वैदानिकता के बारे में निणय करने का अधिकार है। किसी विधि के कियायित होने के एक माह के अंदर परिषद अपना निषय दे देती है। यदि विधि को कोई अस परिएद हारा अवधानिक घोषित किया जाता है तो वह क्रिया जित नहीं किया जाता । सब्धानिक परिषद के निषय के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती है। इसके निणय सभी प्रधासनिक एव यापिक अधिकारियों के लिए माय होते हैं। व । वस्त । । वन प्रता नवाभाग प्र पण नार के ति तीन वप पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं। 3 सदस्य राष्ट्रपति, 3 सदस्य सहस्य राष्ट्रपति, 3 सदस्य सीनेट एव शेप 3 सदस्य राष्ट्रीय समा हारा निपुन्त किय बाते हैं।

नेपाल मे यापपातिका का संगठन पिरामिड की माति है जिसके तल पर जिला चायालय एव शोप पर सर्वोच्च चायालय अधिरित्रत है। सविधान द्वारा एकल मायपालिका का निर्माण किया गया है। गोवो स ग्राम-प्लायते हैं। वे देश के सबसे होटे यापालय है। इनके डारा स्थानीय एव छोटे ऱ्यापिक विवादो म निणय दिये जाते हैं।

ķ

1

इस नामालय ने एक मुख्य पामाधीय एव छ अन्य यावाधीश होते है। मुख्य यागाधीय की नियुक्ति सम्राट हारा की जाती है। वह इस सम्ब ध में राजसमा के कुछक सदस्यो एव सर्वोच्च प्यापालय के प्यापाधीक्षो से परामश कर सकता है। अप सर्वोच्च "पाघालय 300 मामाधीयो की निमुक्ति सम्राट मुख्य यायाधीय के परामश पर करता है। तदय एव अय यामाधीओं की नियुक्त भी सम्राट द्वारा आवश्यकतानुसार की जा सकती है। मुख्य एवं अयं यायाधीची के पद सम्बंधी बहुताएँ निम्नवत हैं

- (1) वह कम से कम 5 वण तक जिला यावाचीश या अप किसी समान
- (2) वह कम ते कम 7 वप तक अधिवयता के रूप मे कार्य कर चुका हो, याधिक पद पर काय कर चुका हो, अथवा

अथवा 50 Carter etc op cit , p 247

(3) सम्राट की हिट्ट म न्यायनिंद् ही।

समी यायाधीस 65 वप की आयु तक अपने पद पर काय करते हैं। अविध है पूत्र यायाधीत को स्वेच्छा से पह त्याम ना अधिकार है। सविधान म यायाधीत को पदन्यत करने की विशेष प्रतिया का उल्लेख है। समार स्वेष्ट्राप्रकृत या राष्ट्रीय प्रवामत के प्रस्ताव पर एक या अधिक वेदस्यीय एक आयोग नियुक्त करता है वे सम्बच्धित न्यायापीच की अक्षमता एव दुराचार सम्बची आरोपी की जीच करता है। इस आयोग के सदस्यों की योग्यता सर्वोच्च यागालय के यागाभीचा के समान होती है। आयोग हारा यदि अपन प्रतिवेदन म किसी यायाधीश की दुराचार एवं अक्षमता का दोषी होने के कारण उसे दाखित्व सम्पादन म असमय उहराया जाता है तो समाट उसे परच्युत कर सकता है। यायाधीको के कायकाल म जनक वेतन एव सेवा सम्ब भी यर्तों म कोई हानिकारक परिवतन नहीं किया वा सकता। पदनिवर्ति तमा प्रत्य था थाता न भाव हैं।।नभारक भारवधन वहा ।कथा भा धरधा । भागाभार के पहचात स्थायो यायाचीस किसी यायालय स्थया अधिकारी के समक्ष स्रियला के रूप म पैरवी व काय नहीं कर सकता।

होत्राधिकार—नेपाल के सर्वोच्च यायालय को निम्न क्षेत्राधिकार प्राप्त (1) यह अभितेल यायालय है। यह किसी भी ध्यक्ति अथवा पापालय अपनाम के लिए दिण्डल कर सकता है तथा इसके निषय एवं अभिनेस अप ह वधीनस्य यायालया के लिए प्रामाणिक होते हैं।

प्रवास्त्राच्या क म्यूप्रवास्त्राच्या वृत्त् त् . (2) प्रारम्भिक या मीतिक क्षेत्राधिकार—सर्वोच्च यायालय को मौति ्रभाषाच्या विवादी एवं लोक सवा के राजपत्रित शासनाधिकारियों के सास के विरुद्ध वेतन, परच्छुति एव निलम्बन सम्ब भी मामला म गौलिक क्षेत्राधिकार क 1946 मधान में निक अधिकारा का सरक्षक माना बाता है और प्रत्येक भाष है। यह बाजान का स्वाहित के सिन्द्रम्य की देशा में सर्वोड्स बाजालय में आवेदन करने का अधिकार है। यायालय मौतिक अधिकारो के रक्षाय आरेस, भागा एवं व दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश प्रतिरोध अधिकार पुच्छा एवं उत्प्रेषण के लेख जारी कर सकता है।

(3) अपीत्तीय या वुनरावेदनीय क्षत्राधिकार--यह सभी प्रकार के स्वधानिक, अपराधिक एव दीवानी विवादा में देश का सर्वोच्च वधीलीय यायालय है।

पण एवं पात्रामा म्यापना में व्यापना के सम्बंध में समीय यायालय के विरद्ध जनके द्वारा यह प्रमाणित करने पर कि विवाद म विधि सम्ब बी महत्वपूण प्रस्त जनक क्षाच भूद क्ष्मान्य के स्वय इस सम्बन्ध में स तुष्ट होने पर अन्यस्त किया जा सकता है।

ा प्रम्था ए , (आ) अपराधिक विवादों में बचन यायालया के निषया के विरुद्ध वर्षीत की जा सकती है, यदि अधीनस्य प्रायातम् ने 3 वप से अधिक समय का कारावास मा 3000 रुपये जुर्माना का दण्ड दिया हो।

- (इ) शीवानी विवादो म सर्वोच्च याग्रालय म अपील निम्न अवस्थाओं में
- (i) जब विवाद सम्ब धी राधि 5 हजार स्पय से कम न हो तथा क्षेत्रीय सम्मव है
 - (11) सर्वोच्च वायालय को यह विश्वास हो जाय कि विवाद म कोई विधि 'पायालय ने तत्सम्ब ध म प्रमाण पत्र दिया हो ।
 - सम्ब धी प्रश्न निहित है।
 - (।।) विवाद की राधि 3000 रुपय से अधिक हो तथा क्षेत्रीय और जिला
 - (4) सर्वाञ्च यायातय को निम्न यायातय के उन विवादों की समीक्षा (revision) के अधिकार भी प्राप्त है जिनके सम्बंध म अपील की कोई व्यवस्था नहीं न्यायालय के निजय समान न हा । है। उसे अपने निषय पर पुनर्विचार करने अथवा पूर्णत उसे निरस्त करने के अधिकार

भी प्राप्त हैं। बाबालय केवल दो स्थितिया म हो पुर्वाचवार कर सकता है। उपयुक्त सेनाधिकार को सविधान द्वारा अनुच्छेद 70 एवं 71 के अधीन दो मागो—(अ) साधारण क्षेत्राधिकार, एव (आ) असाधारण क्षेत्राधिकार—मे वर्गीहत किया गया है। मीतिक अधिकारा का सरक्षण उसका असाधारण क्षेत्राधिकार है।

निरकप-सर्वोच्च यावालय याव व्यवस्था के लीप पर स्थित दश का सबसे वुच्च यामालय है। इस पायालय की स्वत नता एवं निष्पक्षता सम्बंधी आवश्यक स्पतस्या सविधान द्वारा की गयी है। सर्वोच्च वायालय सविधान एवं मौतिक अधि कारो का सप्सक है। उस सविधान विरोधी विधियों की अवैधानिक घोषित करन का अधिकार है। चायाधीशों का कायकाल निश्चित एवं निर्धारित किया गया है। 65 वप की आगु पर उनके द्वारा अवकाश ग्रहण किया जाता है। पदिनवित के परचात के देश के किसी यापालय या अधिकारी के समझ बकालत नहीं कर सकते हैं। उनके वेतन एवं मत्तों की भी उनके कायकाल भे कम नहीं किया जा सकता तथा उनके वेतन सुचित निधि पर भार है। यह सब अयदस्थाएँ यामाधीको को बाहित स्वत नता एव निर्मावता प्रदान करने की हॉस्ट से महत्वपूष है। लेकिन नेपाल के पापिक रक्षा क्वन मे एक छेद फिर भी रह गया जिसके कारण वह अभेध नहीं है। यायाधीखी के कार्यों एवं आचरण सन्त्र पी अक्षमता एवं दुराचार की जांच के लिए आयोग की निमुक्ति की व्यवस्था है। यह व्यवस्था वाहर से देखने पर स तोपप्रद प्रतीत होती है परंतु इसम तीन मयकर दोष है। सम्राट स्वेच्छा से आयोग नियुक्त करता है तथा ्रायोग के प्रतिवेदन पर वह स्वय ही यायाधीश को पदन्युत करने सम्ब भी निणय नेता है। सविधान द्वारा राष्ट्रीय पंचायत को अतिम निषय का अधिकार प्राप्त नहीं राज र कार्या इस सम्बद्ध में अब तोकतातीय देश में बावपालिका सम्बद्धी है। यह व्यवस्था इस सम्बद्ध में अब तोकतातीय देश में बावपालिका सम्बद्धी

को परच्युत करने का अधिकार हैं। ब्रिटेन, मारत एव संयुक्त राज्य अमेरिका की कार पालिका अपने इस अधिकार का अयोग विधानमण्डल के निर्णय के अनुसार करती हैं। इन देशों म विधानमण्डल द्वारा मावाधीयों की जींच एवं पदच्युति के सम्बण म उन कतच्या को सम्पादित किया जाता है जो नेपाल में आयोग द्वारा निमाय जात हैं। ऐसे महत्वपूष मामने के सम्ब ध म एक स्थायी आयोग की नियुक्ति उपयुक्त नहीं है क्योंकि एक सदस्य के अवादनीय रूप से त्रमावित होने की अधिक सम्मावना होती है। कुछ प्रसको का तो यह मत है कि नेपाल म तभी चिक्रमां सम्राट म कड़ित कोर राष्ट्रीय पद्मायत, मित्रमण्डल और यहाँ तक कि यागपालिका भी केवल सम्राट की द्वाया मात्र है। सभी छोटे वर्ड निषय उसके द्वारा किये जाते हैं। नेपाली तर्वोच्च यायात्त्व के पुरुष यायाधीस श्री भगवतीत्रसार हिंह योग्य एवं अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति है। उनकी देख रेख में सर्वोच्च यायासय निरत्तर सम्मान एवं शक्ति अजित हरता जा रहा है। कुछ वप पूर्व सर्वोच्च यायासय ने श्री के आई सिंह को विधि एवं पढ़ीत सम्बंधी कुछेक दृदिया के कारण नवरवादी से मुक्त कर दिया था। सरणीय है वि श्री विह को समाट की सरकार ने पूछ बिनाश एवं कानून के उल्लंबन सम्ब घी बारोपो पर ब दी बनाया था। पाकिस्तान की न्यायपालिका

1962 है के सिवधान के अतगत पाक यायपातिका म सर्वोच्च यायात मा तीम उच्च यायासय एव पाकिस्तान की यायिक समिति शामिस थे। सर्वोध माधातव पाक पायपातिका के विसार पर स्थित उच्चतम पापालय था। इसम एव पाधाव पाक पाधपाधाका कार्यकर १६ १८०० व्यापाधी एवं अस्य पायाधीश होते थे जो विधि हारा निर्धास्ति किये जात थे। द्वरण वाचावाच एवं गुण्याच्याच होते. द्वरण वाचावीत की निर्द्वित राद्यति करता था एवं अस्य यायाधीता की निर्द्वित उण्ण पानाचा के पद की अहताएँ निम्नवत थी—(1) वह पाक नागरिक हो, (2) वह 5 वय तक पाक उच्च पायाचय में मायाचीस के रूप म वयसा 15 वय तक उच्च विश्व तक प्राप्त कर पुका हो। यायालय म अविरिक्त याया-धीद्यों की नियुक्ति की भी व्यवस्था थी। यायाचीत्व 65 वय की आयु तक पदासीन वाचा १० १९८८ १५ ज्या जा जाती. रहते थे एवं सविधानानुसार सह पदच्युत किया वा सकता था। ९४ चारवनागानुकार ० ९ २४ -३४ राज्या २४ व्यक्ता २४ राज्या २४ र शक्तियाँ एव क्षेत्राधिकार —सर्वोच्च यायासय को मौतिक युनरावेदनीय एव परामश्चदायी क्षेत्राधिकार प्राप्त थे।

(1) मौतिक क्षेत्राधिकार के अंतवत उसे एक या अय शासना—प्रातीय एव के द्रीय—संस्व मी विवादा का निषम करने का विकार प्राप्त मा।

(u) दुनरावेदनीय क्षेत्राधिकार निम्नत हु—उच्च यायालया के निषया एव आदेशों के विरुद्ध अपीनें सर्वोच्च यायातय म होती थी, जबकि वह यह प्रमाणित करे

निहित है या उच्च यायालय द्वारा मृत्युरण्ड या आजीवन कारावास का दण्ड दिया गया हो अथवा पायालय की कायवाही में वाषा डालन के कारण किसी व्यक्ति को उच्च पायालय ने दण्डित किया हो । सर्वोच्च पायालय की विदोप अनुमति से भी उसके समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती थी ।

(॥) परामश्रवायी क्षेत्राधिकार के अन्तगत सर्वोच्च यायालय से विधि सम्बची मामले भ राष्ट्रपति परामश ले सकता था। विधि द्वारा सर्वोच्च यायालय के क्षेत्राधिकार म बृद्धि की जा सकती थी (अनुच्छेद 60)।

समोक्षा-सर्वोच्च एव उच्च यायालय का गठन बहुत कुछ स्वत नता के पूव प्रचलित यायिक व्यवस्था पर आधारित या । यायाधीशों को स्वतः त्रता प्रदान करने की व्यवस्था की गयी थी। उदाहरणाध, सर्वोच्च यायालय के यायाधीशा का कायकाल निविचत या, उन्ह केवल निर्धारित रीति से ही पदच्युत किया जा सकता था, यामाधीश अपने सेवा काल के दौरान में अप किसी यायिक पद की ग्रहण नहीं कर सकते थे एव पदनिवत्ति के दो वय पश्चात ही शासन म किसी यायिक पद पर नियुक्त किये जा सक्ते थे। उच्च यायालय के यायाधीश 60 वप तक पदासीन रहते थे। सर्वोच्च यायालय के निणय एव उच्च यायालयों के निणय विधि का प्रश्न निहित होने की सीमा तक अप अधीनस्य पायालयो पर बाधनकारी होते थे। सर्वोच्च यायालय को केदीय व्यवस्थापिका एव सर्वोच्च यायालय द्वारा निर्मित नियमा के अधीन यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान की गयी थी। पाक सर्वोच्च प्यायालय की प्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका या भारतीय सर्वोच्च यायालयो की तुलना म कम थी। विधि सम्बंधी प्रश्नो मे पाक यायालय अतिम निर्णायक नहीं था । सविधान द्वारा 'यायालया को पर्याप्त शक्तिशाली नहीं बनाया गया था। जनरल अयूव का यह मत था वि यदि विधिया के सम्बाय में यायपालिका की अतिम निर्णायक के अधिकार दिये जाते है तो पाक जैसा नवीन देश विकास की आशा नहीं कर सकता। स्पष्ट है कि सर्वोच्च यायालय की यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सीमित थी। उसके द्वारा मौलिक अधिकारो के आधार पर विधियो को अवधानिक घोपित नही निया जा सकता था। यायाधीशो को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता था । ऐसी स्थिति म इस बात की सम्भावना रहती थी कि राष्ट्रपति अपने ही व्यक्तियो को 'यायाधीश के पदो पर नियुक्त करे।

पाक मे सर्वोच्च यायिक परिषद की भी व्यवस्था की यथी थी। सर्वोच्च यायासय के यायाभीश एव उच्च यायासय का एक यायाभीश इस समिति के सदस्य होते थे। समिति की सर्वोच्च यायास्य एव उच्च यायासयो के यायाभीश के भीवार एस सम्बंधी सहिता के निर्माण का अधिकार प्रदान विया गया था। "यायाभीशो के शारीरिक या मानिसक रूप में अस्वस्य होने अथवा राष्ट्रपति द्वारा सुचित किये जाने पर समिति को जाँच के अधिकार प्रास्त थे। यदि समिति के अनुसार सम्बंधित प्राया-

धीरा अपने दायित्व सम्पादन कं अयोग्य होता या तो राष्ट्रपति उसं पद से पृषक कर सकता था। पाव यायाधीचा को उक्त रीति से ही पदच्युत किया ना सकता था।

प्रान्तो म उच्च न्यायातय की व्यवस्था थी। 1962 ई वे सविधान के अत गत पाकिस्तान म पूर्वी एव पश्चिमी पाविस्तान नामक दो प्रान्त थे और प्रत्येक प्रात के लिए मुद्रक पुक्क एक उच्च यायालय या निसम एक मुख्य यायाधीरा एवं राष्ट्र पति द्वारा नियुक्त व य यायाधीच होते थे। उच्च यायालयो म वे ही पाक नागरिक पायाधीस नियुक्त हो सकते थे जो कम से कम 10 वच तक अधिववता या लोक सवा के सदस्य रहे हो। उच्च स्थायालय को विधि द्वारा प्रवत्त संवाधिकार प्राप्त थे। इन यापालया को व दी-मत्यक्षीकरण आदि सेख (wits) जारी करने के भी अधिकार थे।

1917 ई की रुसी ऋषि के फसस्वरूप रूस म साम्यवादी धासन की स्यापना के पश्चात जार कालीन विधि एव याच व्यवस्था का परिस्थान कर विधा गया। यह स्वामाविक भी या नयोकि वास्चात्य वरम्परावत तथा साम्यवादी विधि एव याय ह्य वस्याओं की घारणाओं में आधारभूत अतर है। परम्परागत विद्यात के अनुसार विधि भागतीय अचरण के सावभीय नियम हैं। यायपातिका की स्वत्रता नागरिका के भागवाथ आंधरण क सावभाग गयम हा वाध्यात्वका का स्वत नता गागरका क अधिकारी एव स्वत मताओं के रखा-कवच के रूप में आवश्यक है। लेकिन मास्तवारी जावकार। एवं रवध नधाका के रखान्काच के उन्ने नारायक है। जाने विद्या की सीवि एक वर्गीय वत बारणा का रणाकार जुड़ा करणा का जुड़ा जु वस्था है। वाशास्त्रक ज्यवरण १४०० च १००० च ७०० च १००० च १००० एव एवं सम्बन्धों की रक्षा का साधन है। यूजीवादी समाज में विधि सम्यत्तिग्राह्मिया के प्य सम्ब मा का प्लाका पान ए के कार्य सबहारा को कायम रखती है। हिता का रक्षा करता ह जार जगमन उर्ज रण उपरास्त्र का भावन रखता है। मानस है अनुसार बुर्जुंबा राज्य की चिनि बुर्जुंजा नम की इच्छा है, जिसकी मुख्य विशेषता भागत व अञ्चल ६ श्रुवण १,०५५ ५० । १००५ ३ १०० १० १००५ । उटल १४ व्यक्त एवं तक्षण उस वम की आर्थिक परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होती है। ¹⁸⁸ बुर्जुओ समाज प्रद लक्षण प्रव वर्ग भाषामा । अस्ति । प्रशासन मात्र है। पूजीवादी व्यवस्था में विधि का उद्देश आपिक देस्टि से सबल पंग वाथम भाग छ। द्वांभाषा प्याप्त प्राप्त का प्रदान जात्मक बाद व कावा वम के हिंता की रक्षा करता है। मामस एवं ऐजिल्स में पूर्णीवादी देशा के विधिके वर्गक हिता का रक्षा करना है। गानक एन ए। जनक न प्रजायका वसा का नापन प्रशासन की तीन्न आसोचना की है। विश्विसको के अनुसार विधि सर्वाधिक प्रमाव प्रशासन का ताक काणावना का है। जिस्सा किया के अंद्रार विश्व के वास्त्र के वास धाला का का नह कणा ह ना छात्रात का रूप नारफ कर हुआ ह । वस साववस्य में पूजीवादी विधिक धारणा की स्वीकार नहीं किया गया है। सास्य ्षांव ज्यवस्या न रूपायाचा राजायक वर्षको स्थापन राजा का स्थापन वर्षको स्थापन वर्षको स्थापन वर्षको स्थापन वर्षको स्थापन वर्षको स्थापन वर्षको स्थापन स्थापन वर्षको स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्

51

The Constitution and the Law of the Judiciary of the U S S R 1938, 52 काल मानस, कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा-पत्र 1967

⁵³

The law is merely the will of the dominant class elevated into Yishinsky, A. Y. The Law of the Sould State, p. 13

राज्यों में सबहारा वग शासक वग होता है अत विधि को सबहारा के हितों की रक्षा एव शत्रुओं से उसका सरक्षण करना चाहिए। वह (विकि) नवीन समाजवादी समाज के निर्माण का साधन है और राज्य के लुप्त होने पर विधि का भी जुप्त हो जाना स्वामायिक है। साम्यवादियों के अनुसार जब तक राज्य जुप्त नहीं होता है। सीवयत विधि व्यवस्था को सबल एव सुहढ़ करना आवश्यक है जिससे पूजीवादी व्यवस्था का अत करके समाजवादी समाज के निर्माण का माग प्रशस्त किया जा सके। मानसवादी मापा म विधि सबहारा के अविनायकत्व की नीति का साधन है। याय का औषित्य उसके परिणामो पर निमर होता है। मानसवादियों को हप्ति से विधि एव याय व्यवस्था काति के सबद्धन का साधन हैं। विधि के समझ समानता, निष्यक्षता, 'विधि की उचित प्रक्रिया' पूजीवादी लोकत त्रीय देशों की विधि सम्ब धी वाराणाएँ आसमत है जीर समाजवादी समाज के निर्माण में उनकी भूमिका प्रमुख नहीं होती है, अधिक से अधिक वे केवल द्वितीय महत्व की धारणाएँ हैं।

लाल कान्ति के पहचात सोवियत रूस मे जन यायालयों की स्थापना की गयी । जन यायालय विवादों का निणय परिस्थितया को देखते हुए सामा य बुद्धि के आधार पर करते थे । सभी समाजवादी देखा की माति सोवियत विवि एवं न्याय क्ष्यस्था का लक्ष्य साम्यवाद की प्राप्ति म योग देना है। सोवियत यायालयों का यह दास्यक्ष क्षय साम्यवाद की प्राप्ति म योग देना है। सोवियत यायालयों का यह दास्यित है कि वह सोवियत नागरिकों से समाजवादी विचारपारा एवं पितृ भूमि रूस के प्रति मिक्त की मावना उत्पन्न करें वा सोवियत विचारपारा एवं पितृ भूमि रूस के प्रति मिक्त की मावना उत्पन्न करें वा सोवियत विचारपारा एवं पितृ भूमि रूस के प्रति मिक्त की मावना उत्पन्न करें वा सोवियत विचारपारा एवं पितृ भूमि रूस के प्रति मिक्त की मावना उत्पन्न करें वा सोवियत विचारपारा एवं प्रति भूमि रूप सामजवादी सम्पत्ति, श्रम अनुः वाचन, ईमानदारी, राज्य एवं सावजनिक कत्यों की रिक्षा करें। सावियत रूप की समाजवादी एवं आर्थिक व्यवस्था अर्थात समाजवादी एवं आर्थिक व्यवस्था अर्थात समाजवादी को रूप के समी अपराधियों को क्रोत दण्ड के सित् प्रयत्न करें। सोवियत पायालयं को ऐसे सभी अपराधियों को क्रोत दण्ड दण्ड देना चाहिए जो अपने समाजवाद की रूप समाजवाद की स्थापना में वायक है और ऐसे अपराधियों को विच्य एवं निमृत्य करना चाहिए। विच्य एवं निमृत्व करना चाहिए। विच्य एवं निमृत्व करना चाहिए की विच्य प्रचारा की सिट्य एवं निमृत्व करना चाहिए। विच्य प्रचारा विच्य एवं निमृत्व करना चाहिए। विच्य प्रचारा चाहिए। विच्य एवं निमृत्व करना चाहिए। विच्य प्रचारा विच्य प्रचारा की विच्य प्रचारा की विच्य प्रचारा की स्थापना की निष्य प्रचारा कर सामाजवाद को उद्योग वाचन की स्थापना की निष्य प्रचारा की स्थापना की स्थापना की स्थापना की सामाजवाद को उद्योग सामाजवाद को उद्योग वाचन की सिट्य प्रचार विच्य का स्थापना की स्थापन

सोवियत "याय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ निम्नवत हैं

(1) सोनियत यायापालिका अन्य विसागो (यथा—गह एवं विदेश विभाग) की भाति ही प्रशासन का एक भाग है। यह लोकत त्रीय देशा की माति निप्पक्ष एव स्वत त्र नहीं है। यायपालिका द्वारा याय सम्पादन का काय प्रोक्यूरेटर जनरल एव

⁵⁴ Peoples' Courts

⁵⁵ The Law of August 1938

चराके अधीन व य अधिकारिया के सहसीय से सम्पादित किया जाता है। प्रोग्यूटेटर जनरत को हम सोवियत रूस का महा यापवादी वह सकत हैं।

- (2) सभी यायालया के यायाधीन निश्चित वर्वाध के लिए निर्वाचित होते हैं। उदाहरणाथ, मोवियत रूस के सर्वोच्च यायात्य एवं विशेष यायात्वय के धोरा 5 वय ने लिए सुत्रीम सोवियत द्वारा निर्वाचित किय जाते हैं। जनता पाप के यायाधीत सबसे छोटे होते हैं, जनता द्वारा तीन वय के तिए चूने जाते विविध गणत भीय एव क्षेत्रीय यायालया है यायाधीस जनकी सोवियता हारा 5 व क तिए निर्वाचित विय जाते हैं।
- (3) न्यायालया की एक सी व्यवस्था है। यायालया के समझ विधिक हरिट से सभी नागरिव समान होते हैं।
- (4) प्रत्यक यायालय म यायाधीस के अलावा जन निर्धारक या असेसर (Assessor) में भी होते हैं। वे नियांचित होते हैं। यायाधीस का पद निश्चित अविध ्रा एए ए १ जाराज एए ए १ जाराज प्राप्त के समय हो साम करते हैं। अवराधिक मामला में सामा यत हो अवसर एवं एवं स्वायी वासाधीश करत है। जनस्थानक भागता भ त्यान प्रवासक प्रवास । व्यासक होते हैं एवं ने अध्यक्षता करते हैं। अवेसर हाता है। पापात्राक । पापात्र अवस्था हात है । विभि एवं तस्य सम्बंधी प्रकृतों के बारे से पापाचीक्ष के सहयोग से निचय करते हैं । वाद विवाद में भी वे साम लेते हैं। यद्यपि निषय बहुसत ते लिये जाते हैं लेकिन पायाधीव ना मत मा य होता है। निर्वाचित पावाधीवो एव असेसरी की अपने काम का प्रतिवेदन अपने निर्वाचन क्षेत्र की देना होता है।
- (5) पाणाधीन एव असेसर एक ही गढ़ित हारा एक ही अविध के लिए चुने जाते हैं। दोना के मत्यावतन (recall) की व्यवस्था है। वोवियत रुस म याया भारत है। भारत है निए कोई योग्यता निर्मारित नहीं है, परंतु यायाधीत निर्मारित नहीं है, परंतु यायाधीत निर्मारित निर्मा विधीपज्ञ होते हैं। यायाधीश का पर स्थायी है। पर तु असेसरो का पर अस्थायी है। विषयम केवल 10 दिन काय करत है। किसी विवाद में आवस्यकता एडने पर इस ववाच म भाक का गणा । विका प्रोक्यूरेटर हारा गणत त्रीय प्रेसीटियम की अनु-मति से प्रारम्म की जा सनती है । सर्वोच्च यायालय के यायाधीक्षा के विस्त सधीय प्रेसी हियम की जनुमति से प्रोक्यूस्टर जनस्त के बादेश पर अपराधिक कायवाही की जा सकती है।

भागा ६ . (6) सभी विवाद सुली बदालत म सुने जाते हैं। अपराधी को अपने बचाव 56 Articles 105 109

ना पूज अधिकार प्राप्त है। व सभी 'यायिक कायवाही क्षेत्रीय मापा म होती है। यदि कोई व्यक्ति क्षेत्रीय भाषा से अनविज्ञ होता है तो उसे अपनी मापा के प्रयोग का अधिकार प्राप्त है और ऐसी स्थिति ये दुर्भाषिए की व्यवस्था होती है (अनुच्छेद 110)।

(7) सोवियत याय व्यवस्था में अराजनीतिक अपराधों के लिए कठार दण्ड की व्यवस्था ने अराजनीतिक कार्यों की हृष्टि से यह व्यवस्था श्रेष्ठ है। परन्तु राजनीतिक या समाजवादी क्रान्ति विरोधी कार्या का कठारता एवं निममता-पूबक दवाया जाता है (अनुच्छद 133)। देखहीह के अपराधा का भी निममतापूबक दमन किया जाता है। जनता एवं समाजवादी सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध करने वाले को कठीर दण्ड देने की व्यवस्था है (अनुच्छेद 131)।

म्यायालयों का सगठन

सोवियत रूस में पाय व्यवस्था के बीय पर मोवियत मध का सर्वाच्च ।याया-लय है। उसके नीचे सब गणतानीय सर्वाच्च यायालय, क्षेत्रो, स्वायत्त यणराज्या, एव प्रदेशों के न्यायालय तथा सोवियत सच द्वारा स्वापित विशेष यायालय होत है। सबसे नीचे जन न्यायालय (People's Court) होते हैं।

सोवियत सथ का सर्वोच्च न्यापालय—सावियत रूस का यह सर्वोच्च याया लय है। इसके न्यायाधीस सुप्रीम सोवियत के समुक्त अधिवेशन में 5 वप के लिए निर्वाचित किये जाते है एवं इसके मुख्य वायित्व निम्नत है

(1) सम्पूण सोवियत सघ के यायिक कार्यों का निरीक्षण करना ।

(2) अखिल मधीय एव सहस्वपूण दीवानी तथा अपराधिक मामला (जसे— सीवियत सप की सुरक्षा एव सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध) में इस "पामालय को मौसिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। कम महत्व क दोवानी एव अपराधिक मामलों में इस "पामालय का पुनरावेदनीय क्षेत्राविकार प्राप्त है। मर्वाच्च पापानय का अविवाद समय अपील पुनने म स्पतील होता है। दोना पक्षों का अपील दायर करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अवितिक्त सर्वोच्च पापानय के मुख्य मामाधीक एव सोवियत तथ में महा पाय बादी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी निम्न यायालय म चन रह विवाद को अपने समझ निष्य हेतु प्रस्तुत करने तथा किसी अप पापानय के निष्य पर पुत्राचिचार करने का आदेश दे सकता है। सच गणराज्या के सर्वोच्च एव अन्य पापानयों तथा सोवियत सच के विविद्य पायालया के निष्या च विरुद्ध प्रपी पीठ (1611 beach) को किसी मण्डन के निष्य पर पुत्राचिचार वा अधिवार प्राप्त है। सरकारी कमचारिया द्वारा चल्च-मालत के दौरान होन वाले अपराधा थे सम्बन्ध म निषय का अधिकार सर्वाच्च पायालय को है। उच्च सनिक अधिवारिया

के मामले भी इसी यापालय ने धेंत्रा तमल हैं। समीय गणराज्या क मध्य उलार होन वाले विवादा का यह यायालय निषय करता है।

सर्वाच्च यायात्वयं का एक अध्यक्ष, ज्याच्यक्ष एवं अयं सदस्यगण होतं हैं। 1938 ई म इसकी सदस्य संदया 45 थो। 1946 ई म यह संख्या यहकर 68 हो गयो थो। इसक अतिरिक्त जन निर्धारक (assessors) भी होत हैं। सर्वोच्च पापातप के 5 मुख्य मण्डल (division) हैं—दीवानी, फोजदारी या अपरापिक, सनिक, रेसने एव जनीय यातायात सम्बन्धी । इन मण्डला क अध्यक्ष अपने अपने मण्डला की बैठका की अध्यक्षता करते हैं एवं कार्यों का निवसन करते हैं। प्रत्येक मण्डल सर्वोच्च पायालय मो अपने कार्यों के सन्त प म प्रतिवदन देता है। सर्वाच्च यायास्य के यायाधीया की सस्या तिवधान द्वारा निविचत नहीं हैं अपितु तवोंच्य सीवियत द्वारा निविचत की जाती है। गणराज्या (Union Republics) के तर्वोच्च यायात्वय के मुख्य यायाचीय सर्वोच्च न्यायातय के पदेन सदस्य होते हैं। यायाधीस पद के लिए किसी विशेष योग्यता का उत्तेख नहीं है, पर हु विधि विदेशक एक अनुसवी व्यक्ति ही यामधीस के पद पर नियुक्त किये जाते हैं।

सर्वोच्च यायालय जब मौलिक क्षेत्राधिकार सम्बन्धी निसी विवाद पर विचार करता है तो उसकी युनवाई एक यायाधील एवं दो जन निर्धारको द्वारा की जाती है। करता ह ता व्यक्त प्रकार इक वारावत्त पूर्व राजा वाराव्य अस्ति अस्ति वासी हैं। राजस्व माया भवात नाव वायावाय मा पाठ (क्वाक्य) है । पाठ व पाठ विस्तित से हैं । विस्तित के अधिवेशन में तीन यायाधीश माग तेते हैं ।

रूप म तथा प्रवास के सर्वोच्च यायालय को यायिक पुनरीक्षण की यक्ति प्राप्त मही है। वह किसी विधि या मन्त्रिमण्डल के किसी काय को अवैद्यानिक घोषित नहीं विश्व । यह राज्य अमेरिका जसे सभीय देशों की माहि साबियत रूस का भारतकता है। एउटा का सरसंक भी नहीं है और न उसे सविधान की व्याख्या वावातव वाववात का वर्षकात के तरहाण एवं यास्या का व्यास्था पायातय को न होकर सुप्रीम सोवियत की प्रेसीडियम को है।

थि का ग हाकर छुनान जाननक कर नहारकन का हर । सर्वाय गणराज्यों के सर्वोड्ड यायालय—संघ गणराज्य सोवियत सम इं पटक इकाइया है। प्रत्येक सद्य गणराज्य में एक सर्वोच्च यायालय होता है। यह पायालय संघ गणराज्य की याम व्यवस्था के विखर पर स्थित है। इसम एक अध्यक्ष प्रवाह मुद्रय यायाधीस होता है। यायाधीस एवं जेन निर्मादनों को संधीय गणराज्य की सर्वोच्च सोवियत पाच वप के निए निर्वाचित करती है। इस यायालय का दीनानी एवं अपराधिक मामना म मौनिक एवं पुनरा

वेदनीय (अपीलीय) क्षेत्राधिकार प्राप्त है। मणराज्य की सर्वोच्च प्रसासकीय संस्थाओं वदमान (जमावान) जमानकार कार्य है । जन्म ज व्यापनान जमानकार की प्रेसीवियम एवं यामवादी (Procutator) तथा मनी म जावनारता, राजार्ज मा अव्याप्त १४ राज्यात्म (Associator) वस्त जा न जा के विद्ध अभियोग जस गम्भीर मामलो म सम् गणराज्य के गोसल्य को मौसिक

क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उसे गणराज्य के अय यायालयों के निणयों की निरस्त करने का भी अधिवार है। यह न्यायालय गणराज्य एवं उसकी अय इकाइयों के "याय प्रशासन का निरोक्षण करता है।

सावियत सघ म 15 सधीय गणराज्यों के सर्वोच्च यायालय हैं। इसी प्रकार प्रायंक स्वायत गणराज्य (Autonomous Republic) में एक सर्वोच्च यायालय होता है। इसके यायधीशों को स्वायत्त गणराज्य की सुप्रीम सोवियत द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इन यायानयों नो दीवानी एवं अपराधिक मामलों म मौलिक तथा पुनरावेदनीय दोना ही प्रकार के लोगाधिकार प्राप्त है।

विशिष्ट 'यायालय एव पच फसला न्यायाधिकरण---सोवियत रूम मे अनेन प्रमार के विशिष्ट पायालयहै, यथा----नाल न्यायालय (Juvenile Courts), भू 'पायालय (Land Courts), भैनिक 'पायालय एव पच फैसला वायाधिकरण (Courts of Arbitration)। विशेष सैनिक पायालया की आवश्यकता सोवियत रूस की सुरना एव सैनिक अनुशासन के रक्षाय की जाती है। रख्ये एव चलीय यातायात प्रणाली एव तत्मवन्धी परिस्थितियों के फलस्वरूप विगेष वाहन 'यायालया (Special Line Courts) की स्थापना की गयी है। यन विवादों को पच प्रमाना 'याया पिकरण द्वारा तय किया जाता है। यह 'पायाधिकरण शासन द्वारा तो या अधिक प्रकार सम्बाद के सम्बन्ध भ निष्य होत स्थापित किये जाते हैं।

जन "पापालय-सोवियत रूस म जन "पापालयों (People's Courts) के मापाधीक्षा का निर्वाचन जिला के नार्यारको द्वारा सावमीम प्रराक एव समान मता- पिकार के लिए किया जाता है। इन त्यायालया को केमीनिक केनापिकार प्राप्त है। दीवानी और फौजदारी विवाद सवप्रथम इन्हीं "याया- क्षीमी में सापर किये जाते हैं। सम्प्रीत, और फौजदारी विवाद सवप्रथम इन्हीं "याया- क्षीम में सापर किये जाते हैं। सम्प्रीत, अिक, विकाद सवप्रथम इन्हों "याया- क्षीम कीनाधिकार के जाती है। सम्प्रीत, अकार कार स्वाप्त की चौरी, अके, कपट, सक्ता एव अधिकार के बुल्योग सम्बन्धी भामले और शासन के विकट अपराय फौजदारी केनाधिकार के अन्त्रपत छाते हैं। यह सीवियत इन्हें के जिला स्वरीम पामल मंत्रपति केये जाते, इस सम्बन्ध में निजय सम्बन्धित कर के जिला स्वरीम पामल स्वाप्त है। एक जिले में कितन जन "प्राप्ताच्य स्वाप्त किये जाते, इस सम्बन्ध में निजय सम्बन्धित कप गणराज्य पर स्वाप्त गण वां जन निर्धार्थ (assessors) होते हैं। एक जन "प्राप्ताच्य म एक "प्राप्ताच्याच पत्र जन निर्धार (assessors) होते हैं। प्रयोक जन निर्धारक नेवल 10 दिन ही स्थायालय काम काम करता है। "प्राप्तीचों के विष्य काई योग्यत निर्धार निर्मा कियो निर्मा कियो जाते है। जनता द्वारा "प्राप्ताचीया एव जन निर्धारकों के प्रत्यावचन ((ccall)) की मौन की जा सनती है।

साथी यायालय (Comradely Courts) सबसे निम्न यायालय हैं , यायालयों ने यायाणीयों का निर्वाचन सम्बन्धित व्यक्ति-समृह द्वारा किया

इन न्यायालयों के यायाधीस विधि के ज्ञाता नहीं होते । इनकी स्थापना प्रत्येक कार खाने, जेल, आदि अय सस्यानों म की बाती हैं एवं ये उस सस्या विशेष से सम्ब धत व्यक्तियों के विवादों म निषय देते हैं। यह यायानय मारत की याय-पायतों के समान हैं। सोवियत सप का प्रोक्यूरेटर जनरस (महान्यायवाची)

सोवियत सविधान द्वारा विधि पालन की सुनिस्चित करने के लिए सर्व निरीक्षणात्मक यक्तिया प्रोक्ष्यरेटर बनरल या महायायनावी को प्रवान की ग हैं। अ महा यायवादी का प्रमुख दायित्व एव काय यह देखना है कि सोवियत सप के सा म त्रावची एव सस्यावो तथा उनके अधीनस्य अधिकारियो एव नागरिको द्वारा सोवियर विधि का पालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी भी राजकीय सस्या एव पदाधिकारी के अवैधानिक निषय के विरुद्ध उसे अपीत करने का अधिकार प्राप्त है। प्रताचकारा वा जवजाराकः राजप करने वासलो की बीच करने तथा अपराधी के वत भारताच्या नाम्यारः वास्त्र । वास्त्र के वाच का अधिकार प्राप्त है । यायासया के अनुचित प्रदेश के निषयों के विरुद्ध वह अपील करता है। अपराध के संदेह पर किसी नाम ५४ जानक भाजका भाजक जह जह जारेस है जिस्सा है एवं यापालयों है निषदा की किया वित करता है।

पा परका ए । सोवियत समाजवारी संधीय रूसी गणराज्य म संवप्रथम 1922 🚦 में इस वाविषय धंगाजवाचा धंगाजवाचा धंगाजवाचा भंगाजवाचा भंगाजवाचा भंगाजवाचा धंगाजवाचा पद का व्यवस्था का गया था। १८८० व वर वर्ष वर्षा गया है। महा-परत्तु इसके प्रचात इसका नाम बदलकर प्रोक्यूरेटर जनरत कर दिया गया है। महा-परस्तु इत्तम पश्चात २००० जान जनगण्य गण्य विष् विष् विक्षित क्रिया चाता है। मा भाषेत अनेक प्रोक्यूरटर या वायवादी होत है। प्रत्येक सुच गणराज्य, स्वायत ग वधान वनक मानुराज्य । राज्य, क्षत्र या प्रदेश म एक यायवानी (त्रीयपुरेटर) होता है । इनकी नियुक्तियों बप व लिए की जाती हैं।

^{(वध्}ना ^{जातम} द , सोवियत सप म विधि की एक्ट्यता स्थापित करन म सर्वोच्च वायासय स मी अधिव महा यायवान्त्रे का योग है। व्यवहार म सोवियत महा यायवादो सवराक्तिमान मा बाधव महा बाचनाः । भारताः २ : -भण्यः च व्यक्तारं वह समाजवाने विधि का स्तकः है। डाजस्टर १ अनुनार भागपुरदर जनस्त साम्यवादी रूत्र हास निर्देशित सवहास अधिनामकरच की प्रमुख अन्त ग्रीक्त हैं। ⁸² 59 Articles 113-117

⁵⁹ Anticia 113-117
60 Carter, Renney & Hez The Government of Societ Union, op al. P 130 Vubinsky The Las of the Sound State op cut , P 537

^{62 ·} Procurator General is an integral lever of the proletariat dieta

साम्यवादी चीन मे न्यायपालिका

साम्यवादी चीन मे यायालयों का मुत्य काय सोवियत यायालयों की मौति समाजवादी व्यवस्था की रक्षा एवं उसके शत्रुकों का विनाश करना है। श्रमिक एवं राज्य के अनुशासन तथा व्यवस्था का उल्लंधन करने वाले व्यक्तिया को उनके समाजवाद विरोधी कायों के लिए कठोर दण्ड देना यायपालिका का प्रमुख दायित्व है। बीन मं नागरिकों का यह सवैधानिक कलव्य हैं कि वे सविधान एवं विविध का पालन करें श्रमिष अनुशासन को माने तथा सामाजिक नैतिकता को रक्षा करते हुए व्यवस्था एवं शानित वाचे र वाचे पालन करें श्रमिष अनुशासन को माने तथा सामाजिक नैतिकता को रक्षा करते हुए व्यवस्था एवं शानित वाचे र जनवादी चीनों गणराज्य में यायपालिका शासन का पुषक एवं स्वत न वाने रहे । जनवादी चीनों गणराज्य में यायपालिका शासन का पुषक एवं स्वत न वाने नहीं है अपितु प्रधासन का अभिन्न अग है। को मिटाग चीन के अतगत मारत या अमेरिकी वाय-व्यवस्था जसी याय प्रणाली नहीं यी। विधि के शासन वा मी चीन में अभाव था। याय बोडे से व्यक्तियों को हृष्ये। विधि में सम्यावित किया जाता था। 1949 ई में साम्यवादियों के हृष्यों में सत्ता आने पर को मिटाग चीन की प्याय व्यवस्था नितिक व्यवस्था के अनुरूप विधि के सिहताकरण हेतु एक आयोग को स्थापना की गयी। 1949 ई से 1954 ई तक चीन का शासन अस्यायी सिविधान (Common Programme) के अनुसार चलता रहा। 1954 ई में नवीन सविधान विधान पराम हुआ।

साम्यवादी चीन की याय व्यवस्था की विशेषताएँ निम्नवत् है

(1) साम्यवादी चीन की यायपासिका स्वतः न है। वह केवल विधि के अधीन है। हर नागरिक विधि को होट्ट से समान है। लेकिन साम्यवादी चीन में यायालयों को विधानमण्डल की विधिया को अवधानिक घोषित करने की स्वत प्रता नहीं है और न वे विधियों की आस्था हो कर सकते हैं।

(2) सभी यायालया क यायाधीश सम्ब धत जन काँग्रेसा द्वारा निवाधित किय जात हैं। अय यायाधीशों को उस स्तर की सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। सर्वोध्य न्यायालय क यायाधीश के त्रीय द्वासन द्वारा नियुक्त किये जात हैं । अपितु वे स्वायी सिमित (Standing Committee) द्वारा नियुक्त नहीं क्यि जात हैं। कुछ यायाधीशा को कान्तिकारी नंताओं और शेष को विधि विश्वयक्षा म से चुना जाता है। विची नावीन यायाधीशों को प्रारम्भ म प्रशिक्षण मी विद्या जाता है। चीन म न्यायाधीशों को प्रारम्भ म प्रशिक्षण मी विद्या जाता है। चीन म न्यायाधीशों को प्रारम्भ म प्रशिक्षण मी विद्या जाता है। चीन म न्यायाधीशों को प्रारम्भ म प्रशिक्षण मी विद्या जाता है। चीन म

(3) साम्यवादी चीन के यायालयों मं जन निपारना (Assessors) की निपुक्ति भी की जाती है। इनकी नियुक्तिया के दो साम हैं—(1) याय प्रधासन का

torship directed by the party '-J Towster Political Power in the U.S. R., 1917-47

^{63 1954} ई के सविधान को Organic law की सना दी जाती है।

⁶⁴ Articles 73 78

जनता से सम्पक हो जाने के कारण यायालयों में रचनात्मक प्रवत्ति का उदय होता हैं, एव (2) यायाघोद्या पर सावजनिक निय नण स्थापित ही जाता है। सभी जन नियरिक स्थायी एव निवाचित होते हैं। वह उत्पादन सम्बंधी पूण ज्ञान होता है। आधे जन निर्धारक स्त्रियाँ होती हैं। प्रत्येक का कायकाल दो वप होता है। एक वप म वे केवल 10 दिन काय करते हैं। निषय बहुमत से लिये जाते हैं।

(4) अपराधों को आत्मरता का अधिकार प्राप्त है। वे स्वय या वकील द्वारा अपनी परवो कर सकते हैं (अनुच्छेद 76)। लेकिन सम्यवादी चीन में निजी वकीत नहीं हैं। सरकारी वकीलों की एक तम्बी मुची शासन द्वारा तैयार की जाती है, अमि युक्त को इनम से ही किसी को अपनी आस्मरक्षा (परवी) के लिए चुनने की स्वत प्रता है। चीन में अधिवक्ता (बढ़ीस) राज्य एवं बनता के हिंवों को ध्यान में रखकर ही अमिपुक्त के बचाव की पैरबी करते हैं और यायातय को अपने वायित्व के सम्पादन म योग देते हैं।

(5) राज्य की सुरक्षा सम्बन्धी विवादों की खोडकर शेष सभी विवादों की वन पापालय में सावजनिक सुनवाई होती है (अनुच्छेद 76)।

पाय प्राप्तारम् अपनार शास्त्र । (१७४० व. १८) । (6) यायिक कायपद्धति सस्त है। निषय छोझ् विये जाते हैं। चीन म याया-त्य शिक्षा एव सुषार के कतव्य सम्पादित करता है। अधिकतर सम्पत्यता एव सम भौते पर बल दिया जाता है।

् १५ (२५), कार्य ए . (7) अधिकास मामलो म कठोर दण्ड नहीं दिया जाता लेक्नि काचि विरोधी भायों को कठोरतापुर्वक अवस्य दवा दिया जाता है। अय अपराधों के तिए दण्ड एव तुषार की नीति का अनुसमन किया जाता है। मरसुदग्ह के सम्बच म उच्च पायालय का अनुमोदन आवश्यक होता है।

(8) चीन के सभी यायालय जिस जन कायस द्वारा चुने जाते हैं उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उदाहरण के लिए सर्वोच्च यायालय राष्ट्रीय जन-काँग्रेस या जा स्थापा हास ए । ज्याद्वार होता है । इसी प्रकार, स्थानीय जन ऱ्यासावय स्थानीय हथाथा वातास म नाम जना जना जना कार्या है। हैं और उनके समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते भागभाग ए बाद का प्राप्त है। इस अब म चीन म यायपालिका विधानमण्डल का सहायक अब है। सर्वाच्च है। १० वर र राज्य वार्यायका विकास के अधिवेदाना एवं उसके नाद विनासे म साव विता है। प्रत्यक यायालय के बच्चात को उसे निर्वाचित करने वाली बन कांग्रेस साधा साम्यवावी चीन का यायिक सगठन सिवपान के अनुसार चीन में तीन प्रकार के न्यायालय हैं

(1) सर्वोच्च जन पायातय (The Supreme People's Courts), 65 Articles 79 80

- (2) स्यानीय जन पायानय (The Local People's Court) और
- (3) विदिष्ट अन न्यायालय (The Special People's Court) ।

सर्वाच्च जन म्यामालय—यह साम्यवादी चीन का सर्वाच्च पागालय है तथा यायिक पिरामिड के विक्तर पर आसीन है। देश के सभी यायात्रया पर इसे निरीक्षणारमक क्षेत्रापिक्षर प्राप्त है। इसका एक अध्यक्ष होता है, वहीं मुख्य यायाधीश कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ उपाध्यक्ष, शाखाका के मुर्ट यायाधीश एव उपमुख्य यायाधीश, यायाधीश एव उपमुख्य यायाधीश, यायाधीश एव उपमुख्य यायाधीश, यायाधीश एव उपमुख्य यायाधीश, यायाधीश कि व्याप्त होते है। यायालय का अध्यक्ष राप्तीय जनकार्यक्ष द्वारा निर्वाचित होता है और उसी के द्वारा साधारण बहुमत से पवस्तुत किया जाता है। होप न्यायाधीशा की यायालय की यायिक समिति के सदस्यो या स्यापी समिति (Standing Committee) द्वारा निर्वाचित किया जाता है एव व उसी के द्वारा परच्युत विच जा सकते हैं। उप-व्यायाधीश याय म त्रालय (Ministry of Justice) द्वारा नियुक्त किय जाते हैं।

सर्वोच्य जन-यायाजय के दोवानी एव फीजदारी दो विभाग होते हैं। इस गायालय को दोनो---भोलिक एव पुनरावेन्द्रीय---क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। उच्च त्याया स्वया एव विशिष्ट जायामधों के निश्या के विरुद्ध अपीले सर्वाच्य प्रधासन म होती है। इसने अतिरिक्त जायिक निरीक्षण की पद्धिन के अधीन सर्वाच्य अनवादी प्रोक्प्रदेटर हारा जिन विवादों की भूमना दो जाती है उनकी सुनवाई यायालय हारा की जाती है। विधि हारा कुछ अय मामले भी मौतिक रूप म इसके भेत्राधिकार में आते हैं।

स्मानीय जन 'यापालय-स्थानीय जन-यायालय के तीन प्रकार हैं---उच्च, मध्य एव प्रारम्भिक जन जायालय । उच्च 'यायालय की सक्या 28 है। यह मारत के उच्च 'यायालय के सम्बन्ध है। अध्य जन यायालय जिनकी सरया 200 है, भारत के जिला त्यायालयों के समान होते हैं। प्रारम्भिक जन 'यायालयों (Basic People's Courts) की सच्या 3000 है। ये छोटी अदालते हैं। उच्च यायालयों की स्थापना के त्रीय सस्कार करती है। जिला एव प्रारम्भिक जन त्यायालयों की स्थापना प्रातीय का स्थापना की जीवी है।

प्रारम्भिक जन पायालया को बाउण्टी, नगर पायानयो एव जिला पायालया तथा स्वायत्त कारण्टी पायालया मे वर्गोकृत विद्या गया है। विशेष विवादा के लिए जन पायापिकरणो (People's Tribunals) की भी स्थापना की जाती है। स्थापीय जन यायालयां के अध्यक्षा को समान स्तरीय जनकारीय द्वारा निर्वाचित किया जाता है और जाध्यक्षा तथा जय पायाधीको को समान स्तरीय प्रशासनिक पासन द्वारा निगुक्त एव परच्युत किया जाता है। इन्ह दीवानी एव फौजदारी दाना प्रकार के धेनाधिकार प्राप्त हैं।

विशिष्ट जन न्यायालय—इनने अतगत सनिक रेलने, यातायात एव जलीय यातायात यायालय आते हैं। इन यायालयो का सगठन राष्ट्रीय जन-काग्रेम द्वारा

818 | आपुनिक सासनत त्र

इनको स्यापना ने समय निर्धारित कर दिया जाता है। 1953 ई. म. 'सायी धर्मिक पामालय' (Comrade Workers Courts) की स्थापना की गयी है। यह पायालय विसी कारसात या सस्या क श्रीमका एवं सहयोगी कमचारिया द्वारा मगठित किया जाता है।

जन प्रोक्यूरेंदरेट (The People's Procuratorate) (महान्यायवादी)

भोक्यूरटरेट की सम्या चीन गणराज्य म सोवियत रूस की मीति विशिष्ट स्थान रताती है। मुख्य श्रोक्यूरेटर की शक्तियाँ अत्यात व्यापक हैं एव उसके भैयाधिकार के अधीन धासन क समी जग एव व्यक्ति आ जाते हैं । विशिसकी के अनुसार मोवियत प्रोरपूरेटर सम्पूष सोवियत विधि-स्पनस्या का निरोक्षक साम्पवारी दल एव सोवियत मत्ता का नेता तथा समाजवाद का समयक होता है। चीन क मुख्य भोगयूरेटर की स्थिति भी ऐसी ही है।

चीमी गणराज्य का सर्वाञ्च जनवादी प्रोक्यूरेटर का एक कार्यासय है। प्रोक्यू रेटर इसका अध्यक्ष होता है। प्रमुख प्राक्यूरेटर राष्ट्रीय जन काँग्रस द्वारा ४ वर के १८८ इतन। जन्मका शास्त्र १ म्युज नामूज्य अपूर्ण करणाव अस्त जन्म नव न तिए निर्वाचित होता है और वह उसी के द्वारा पदन्युत किया वा सकता है। प्रस्य प्राक्त्रदेटर के अतिरिक्त इस कार्यांत्य मं उप मुख्य प्रोक्यूरेटर, प्रोक्यूरेटरमण एक प्रोक्यू-रेटर समिति के अस सदस्य होते हैं वो राष्ट्रीय वन-कांग्रस की स्थायी वन-समिन-हारा नियुक्त एव पदच्युत किये जाते हैं। सर्वोच्च वनवादी प्रोक्यूरेटर का काय : देखना है कि राज्य परिषद के सभी विमागो, राज्य के स्थानीय जगा राज्य के विमा विषया है। ज पान करने वाले व्यक्तियों एवं नागरिका द्वारा विधि का पासन किया बात है। प्राक्यूरेटर जन-कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होता है एव उसे या सनावसान कास है। अनुस्तर जान्याम् प्रतिवेदन प्रमुत करता है। अप्रमुख या के प्रीय प्रोक्टरेटर भ रचावा भागाम अवस्ता तावाच्या है । इनका कायक्षेत्र विधि द्वारा क कार्यात्वा है। स्थानीय एवं क्षेत्रीय प्रोक्यूरेटर कार्यात्य सर्वोच्च प्रोक्यूरेटर कार्या त्ववास्य हात्रा ह। त्वासार हे काय करते हैं । स्यावीय प्रोक्यूटेट स्यावीय वास्त् के हस्तक्षेप से स्वतंत्र होते हूं।

भोक्यूरेटर यायालया से सम्बन्धित होते हैं। यह विधि का विपक्तत सरसक है। अत यह उन सभी अपराधो एवं सामसो की छानबीन करते हैं जिनका सम्बच माति वर पर का प्रमाण प्रमाण के क्षांकियों के अधिकारों का रक्षक भी हैं। चीन में बन प्राथातय या जन प्रोनपूरेटर कार्यातय के निर्देश पर ही कोई व्यक्ति व दी बनाया जा सकता है। ा.... ६ . वया साम्यवादी देशी (सोवियत रूस एव चीन) वे यायपासिका स्वत व है ?

साम्यवादी देशों म यायपालिका प्रशासन का एक जम होती है और उसका

मुख्य उद्देश्य समाजवाद की उसक धनुओं से रक्षा करना है। सोवियत रूस के सवि धान के अनुच्छेद 112 म यह कहा गया है कि यायाधीश स्वतन्त्र है और वे केवल विधि के ही अधीन हाते हैं। परन्तु पश्चिमी विचारका के अनुसार यह व्यवस्या स देहा स्पद है। साम्यवादी देशा म लोकतन्त्रीय देशो की मांति यायपालिका की स्वत त्रता सम्बन्धी धारणा म विद्यास नही किया जाता और न यायपालिका स्वतान ही होती है। 'यायाधीश साम्यवादी दल के सदस्य होते हैं और दल की विचारधारा में जनका पुण विश्वास हाता है। न्यायाधीश पोलियान्स्की के अनुसार, "यायपालिका राजसत्ता का एक अग है और इस कारण वह राजनीति से पथक नहीं हो सकती। याम पालिका का राजनीति से पुथक रखने की माँग कभी भी किसी परिस्थिति म पूरी नहीं हाती है।"" सर्वोच्च पामालय के यायाधीशा की नियक्ति विधिक योग्यता के आधार पर नहीं होती है। वे निर्वाचित होते है। उनके प्रत्यावतन की भी व्यवस्था है। अत उनका कामकाल सनिध्वित नहीं हैं। ऐसी स्थित म यायाधीश के लिए निष्पक्षता एव स्वत ततापूनक काम कर सकना सम्मव नहीं है। प्रोक्यूरेटर जनरल एव प्रोक्यू-रेटरो के कारण सोवियत रूस के सर्वोच्च यायालय की स्वत नता अत्यधिक मीमित है। यही कथन चीन के सर्वोच्च यायालय पर लागू होता है। सोवियत रूस म पाय-मात्री न्यायपालिका के अधिवेशनो मे उपस्थित होकर उसका माग निर्देशन करता है। यायपालिका के क्षेत्र म कायपालिका का इस प्रकार का हस्तक्षेप यायिक स्वतात्रता का निषेध है। चीन व रूस में सर्वाच्य यायालय का मुख्य यायाधीश एव अय यायाधीश अनिवाय रूप से साम्यवादी दल के प्रमुख नेता होते हैं। डायबली (Diablo) के अनुसार सावियत सर्वोच्च 'यायालय के निणयो का कोई स्वत न महत्व नहीं होता है क्योंकि सोवियत रूस की केन्द्रीय कायकारिणी परिषद की प्रेसीडियम उन्ह अनुमोदित करती है। सविधान की रक्षा एव विधियों की वैधानिकता का दायित्व सयुक्त राज्य अमेरिका म सर्वोच्च यायालय पर है जबकि सोवियन रूस में दूरवाइनर (Turubiner) के अनुसार (दल) की के द्रीय कायकारिणी परिपद एव उसकी प्रसी डियम को प्राप्त है। सर्वोच्च यायालय तो केवल मत (opinions) व्यक्त करता है। चीन में भी यही स्थिति है। यायाधीओ द्वारा शामकीय नीति का अनुगमन किया जाता है। आग के अनुसार सोवियत सर्वोच्च यायालय को अमेरिकी सर्वोच्च याया लय की तुलना में बहुत कम स्वतात्रता प्राप्त है। 69

साम्यवादी देशो म 'व दी प्रत्यक्षीकरण' की कोई व्यवस्था नहीं है यद्यपि सवि-

^{67 &#}x27;Judiciary is an organ of State power and therefore cannot be outside politics. The demand that judiciary remains outside of politics, is no where and under no circumstances realised."
——Polianty

⁶⁸ Ogg & Zink Modern Foreign Governments, p 876

820 | आधुनिय दासात व

पान प्रत्यक अपराधी का अपने बचाव ना अधिनार प्रदान नरता है। इसका परिणान यह है कि साविष्य रूस एवं चीन फ साम्यवादी सासना व जीवमानन जेला एवं चिविरा म सक्क्ष रहत हैं।

युगोस्लाविया की न्याय-व्यवस्था

मुगोस्लापिया को व्यायपालिका एकोक्कत है। कि विनिन्न विवादा को हत करण के लिए विधि द्वारा स्वाधित विद्याप यावालया को व्यवस्था है। दूगास्ताविया म कन्द्र यावालय, को नेया यावालय है। दूगास्ताविया म कन्द्र यावालय, हो नेया यावालया है। दून यावालया का सम्वप कामा य विवादा स होता है। कन्द्र सर्वोच्च यावालय हैं। दून यावालया का सम्वप कामा य विवादा स होता है। कि सर्वोच्च यावालय है। कि सर्वोच्च यावालय स्वयं उच्च यावालय है। आविष विवादा का निषय व्यापारिक यावालय (Commercial Courts) द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त सनिक यावालय मी हैं। यच प्रसत्ता विवादित हैं। योवालय के अतिरिक्त सर्वेवानिय यावालय हैं। ये यावालय के अत्राधिकार निर्वादित हैं एवं उनम परिवतन किया जा सकता है। वै वपने करूव सप्यादन म यावालय पूण स्वतः है कीर सविधान तथा विधि के जनुसार नाम करने के लिए बाध्य हैं। वि

पायालयो म यायाधीया के अतिरिक्त जन निर्पारक (assessors) भी होते हैं। न्यायाधीय एव जन निर्धारक सम्बंधित सामाजिक एव राजनीतिक सपुदाय की परिपद द्वारा निर्वाचित एव निर्धारित रीति से परपुत किये जा सकते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन का भी विधान सम्भव है। ²⁶ विवादों को खुली अदालत म मुना जाता है। ⁵ 'मायालया में यायाधीय पीठ (bench) के रूप म बठते हैं। "

यूगोस्लाविया का सर्वोच्च 'यायालय

सविधान के अनुच्छेद 240 के अनुसार यूगोस्लाविया म सर्वोच्च यायासय का सगठन एव क्षेत्राधिकार विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस यायासय के दागिरव अप्रवत हैं

⁶⁹ Article 132

⁷⁰ Article 139

⁷¹ Chapter XIII of the Constitution

⁷² Article 134

⁷³ Article 136

⁷⁴ Article 137 75 Article 141

⁷⁶ Article 140

⁷⁷ Article 139

- (1) महत्वपूष मामला सम्बाधी सिद्धा तो एव उनके वारे म सामा प परा-मशदायी मत व्यक्त करना।
- (2) सधीय विधि-व्यवस्था के अनुसार गणतात्रीय सर्वोच्च न्यायालया के निणयों के विरुद्ध अपीलें सुनना।
- (3) सपीय विधि का उल्लंधन करने वाले वैध यायानयों के निणया की विधिक व्यवस्था करना !
 - (4) प्रशासकीय विवादा की सुनवाई करना।
- (5) विभिन्न गणराज्या के यायालया के क्षेत्राधिकार सम्बंधी विवादी का निगय करना।
- (6) सधीय विधि द्वारा निर्धारित अय दायित्वो का सम्पादन । सवद्यानिक प्राचानय

यह यायालय विधियों के सवैधानिक औदित्य के सम्बाध म निणय देता है। यायालय द्वारा सवैधानिकता एव वधानिकता सम्बन्धी मामला की समीक्षा की जाती है। यह संधीय समा को अपना प्रतिवदन देता है और सवैधानिकता विधानिकता एव मौतिक अधिकारों के रक्षाय आवश्यक विधियों के निणय का सुक्षाव देता है। 8 हा यायालय में अरुपक्ष एवं 10 अप ग्यायाधीय होते हैं। यायालय के अध्यक्ष एवं अप यायाधीश को का अध्यक्ष एवं अप यायाधीश को अहं वे पुन केवल एक बार आठ वर्ष को अलिए निवंधित किया आता है। वे पुन केवल एक बार आठ वर्ष को अवधि के लिए और निवंधित की सवते है। आधे यायाधीश प्रति चार वर्ष पश्चात निवंधित होते हैं। इस यायालय के यायाधीश किसी गण-तनीव परिषद या अन्य किसी राजनीतिक एवं कायपालिका अधिकरण के सदस्य नहीं हो सकते और न काई अप राजकीय यह ही प्रहण कर सकते है। यायाधिशों को अपने कायकाल के पूर्व पदस्यां की स्वत नता प्राप्त है। किसी यायालय झारा यायाधीश को यदि फीजदारी अपराध का दोषी वाया जाता है और कारावास का दण्ड दिया जाता है यह शारिरिक होंट्ट से वे स्थायी रूप के अध्यक्त हो जाते हैं तो उष्ट पदस्यत किया जाता है या शारिरिक होंट्ट से वे स्थायी रूप के अध्यक्त हो जाते हैं तो उष्ट पदस्यत किया जा सकता है।

इस यायालय क निम्न काय हैं 80

- सघीय विधि, गणत नीय विधि तथा अय नियमो का क्रमश सघीय विधि एव अधिनियम की हरिट से औजित्य निर्धारण ।
- (2) संधीय शासन एव गणराज्यो, परस्पर गणराज्यो के मध्य एव अन्य समुदाया तथा क्षेत्रा के अधिकार एव कत्तत्व्य सम्ब घी विवादा का निर्धारण ।

⁷⁸ Article 242

⁷⁹ Article 243

⁸⁰ Article 241

- (3) यायालया एवं संघीय अभिनरणा, यायालया तथा विभिन्न क्षत्रा राजरीय अभिकरणा ፣ मध्य विवादो का निषय करना । करना।
- (4) सिवधान या संघीय विधि द्वारा निर्धारित निर्धी नाय की सम्पादि
- (5) सपीय विधि की सवधानिवता की परीक्षा करना। यदि कोई विधि सिवपान व अनुवृत्त मही है तो सबीय समा को 6 माह के अंदर उस विधि म भावस्यक संशोधन कर देना चाहिए।

वैपानिकता एव सर्वेषानिकता (legality and constitutionality) सम्बची प्रकों को सधीय समा गणत त्रीय परिवदा, संघीय एवं गणराज्या की कायकारिणी परिपदो, सर्वोच्च यायालय तथा अय तथीव यायालयो, गणत त्रीय यायालयो, संघीय जन-अधिवक्ताओ वजत त्रीय संबंधानिक यायालया एवं सामाजिक व राजनीतिक समुदाया की परिवादों द्वारा उठाया जा सकता है। ^{है।} यायालयों की संपीय विधियों की ब्यास्त्रा करने एव उनका अर्थ निश्चित करने का अधिकार प्राप्त है³⁰ तथा सवयानिक यायालय को अवने समठन एव कायपदिति की निर्धारित करने की स्वत वता है। जन-अधिवक्ता

जन-अधिवक्ता (Public Prosecutor) अवराधिक विवास सम्बन्धी कार्यो को सम्मादित करने के लिए पूणक्ष्पेण उत्तरदायों होते हैं। इसके अतिरिक्त विधि के हिया इयन एवं वैद्यानिकता (legality) की रक्षाय भी वे उत्तरदायी होते है विधि एवं सघीय समा की नीति 🌥 किया जाता है। यूगोस्लाविया जनके द्वारा अपने कतब्यों को सम्पादि। अधिवक्ताओं द्वारा सम्पादित वि जन अधिवक्ता को नियुक्त एव प दायित्वो को सनिक जन सधीय जन अधिवक्ता · (Federal Assembly) **₹** 185 जन अधिवक्ताओं की से नियुक्त करता

की रक्षा आवस्पक है। इसके अतिरिक्त विधि-प्रणाली की एकता को अझुण्ण रखना, नागरिको के सगठनो एव सामाजिक व राजनीतिक समुदाया की सर्वधानिक सुरक्षा सभी ग्यायालयो विदोषकर सर्वधानिक न्यायालय का दायित है। 18 सभी विधिया एव नियमो का ग्रुगोस्त्वाविया के सविधान के अनुकृत होना आवस्पक है। 18 स्वाराज्यों की विधियों को गणत नीय सविधान के अनुकृत होना चाहिए और गणत नीय सविधानों की न तो सूर्योस्त्वाविया के सविधान और न गणत नीय विधियों को सविधा के सविधान और न गणत नीय सविधान के विष् रहीत होना चाहिए। 18 यदि गणत नीय सविधान सविधान एवं गणत नीय विधि सधीय सविधान एवं गणत नीय विधि सधीय विधि के विषयों तु ते तो ऐसी अवस्था में सधीय सविधान एवं निर्मम मा सहीय। सभी विधियों एवं नियमों के प्रमाबी होने के पूत्र प्रकाशित कर देने की स्थवस्था है प्रदेक स्थिक को यायालय में अपनी मापा में बचाब करने एवं निम्न सामासों के निणयों के विच्छा अपील करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त विधि द्वारा ही अधिकारों एवं स्वत ज्वाता को निलम्बित किया जा सकता है।

⁸⁷ Article 146

⁸⁸ Article 148

⁸⁹ Article 148

⁹⁰ Article 158

822 | आपुनिन धासनत त्र

- (3) वामालया एवं संघीय अभिनरका, यायालया तथा विभिन्न क्षत्रा र राजकीय अनिकरणा । मध्य विवादी का निषय फरना ।
- (4) सविधान या संघीय विधि द्वारा निर्धारित विसी वाय की सम्पादित
- (5) सपीय विधि की सवधानिकता की परीक्षा करना। यदि कोई विधि सविधान क अनुनूल नहीं है तो संघीय सना को 6 माह के अदर उस विधि म वायस्यक संशोधन कर देना चाहिए।

वपानिकता एव सर्वेषानिकता (legality and constitutionality) सम्बन्धी प्रको को सभीव समा, गणत त्रीय परिवदा, सथीव एक गणराज्या की कावकारियी परिपदा, सर्वोच्च यायातय तथा अस्य तथीय यायातयो, गणत त्रीय सामातयो, संघीय जन-नापवक्ताओं, वणत त्रीय सर्वधानिक यायासया एवं सामाजिक व राजनीतिक समुदाया को परिपदो डारा उठाया वा सकता है। ध यायालयों को समीय विभिन्नो वी ब्याच्या करते एव उनका वर्ष निश्चित करते का अधिकार प्राप्त हैं। तथा संवधानिक यायालय को अधने संगठन एवं कायपद्वति की निर्धारित करने की स्वत वता है। जन अधिवक्ता

भवका। जन-अधिवक्ता (Public Prosecutor) वपराधिक विवादो सम्बन्धी कार्यो भग-भावपाता (२ ४००००) को सम्मादित करने के निए पूणक्ष्मेण उत्तरतार्थी होते हैं। इसके अंतिरिक्त निधि के का सम्मादत करन के 1905 हैं 1905 की रक्षाय भी वे उत्तरदायी हीत हैं 1 निया जाता है। यूगोस्साविया की सेना सम्बन्धी समान दायित्वों को पनिक जन भिवक्ताओं द्वारा सम्पादित किया जाता है। ^{इंड} सभीय समा (Federal Assembly) जावपातामा को निमुक्त एव पदच्युत करती है। गणता त्रों के जन अधिवक्ताओं को जन जाववाक्ता गणत न की कायकारिणी परिपद के परामश्च ते नियुक्त करता 8 183 सवधानिकता एव वधानिकता⁸⁸

भण्या पुर क्यांनिया के द्वारा निस सामानिक, नामिक एव राजनीतिक सम्ब धा की कल्पना की गयी है जनकी प्राप्ति के लिए सविधान तथा विधिक यगस्या 81 Article 249 82 Article 250

⁸³ Article 251

⁸⁴ Article 142

⁸⁵ Article 143

⁸⁶ Chapter VII

की रक्षा जावस्यक है। इसके अतिरिक्त विधि प्रणाली की एकता को अक्षुण्ण रखना, नागरिको के सगठनो एव सामाजिक व राजनीतिक समुवायो की सर्वधानिक सुरक्षा सभी ग्यायालय कि द्याविक है। "र सभी विधियो एव नियमा का ग्रामित्व है। "र सभी विधियो एव नियमा का ग्रामित्व है। "र सभी विधियो के निवधान के अनुकृत होना आवश्यक है। "र सभी विधियो की विधियो को गणत योथ सविधान के अनुकृत होना चाहिए और गणतान्त्रीय सविधान को न तो प्रामेत्व होना चाहिए। सभी या सविधान को न तो प्रामेत्व होना चाहिए। "र पणतान्त्रीय सविधान के निवप रीत होना चाहिए। "र यिव गणत त्रीय सविधान सभीय सविधान एव गणतान्त्रीय विधि सभीय विधि के विषयो है तो ऐसी अवस्था में सधीय सविधान एव विधि माग्य होगी। सभी विधिया एव नियमों के प्रमाशी होने के पूर्व प्रकाशित कर देने की व्यवस्था है प्रश्नक व्यक्ति को यावाल्य में अपनी माग्य न वचाव करने एए निम्न मापालयों के निजयों के विश्व अर्थना का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त विधि द्वारा ही अधिकारों एव स्वतान्त्राओं को निवधिवा विश्व वा सकता है। "र

⁸⁷ Article 146

⁸⁸ Article 148

⁸⁹ Article 148

⁹⁰ Article 158

संयुक्त राज्य ग्रमेरिका की न्यायपालिका [THE JUDICIAL SYSTEM OF THE UNITED STATES OF AMERICA]

समुक्त राज्य अमेरिका में नय एवं घटक राज्या की पृथक-पृथक यायपालिकाएँ हैं, अत इस दोहरी न्यायपालिका (Dual Judiciary) भी कहते हैं । प्रत्यक राज्य नी अपनी पृथक पामपालिना होती है जिसका गठन एवं क्षेत्राधिकार उम राज्य न सविधान द्वारा निर्धारित है। अमरिकी समीव याय-व्यवस्था के सीप पर नमीय सर्वोच्य पामालय अधिष्ठित है। सथीय पायपालिका म सर्वोच्य पामालम के अति-रिक्त 11 सन्टि (अमगदील) यायालय एव 90 जिला (डिस्टिक्ट) यायालय हैं। सार समुक्त राज्य अमरिका को अमणधील यामालया की स्वापनाथ 11 क्षत्रा म, एय जिला यायालयो की दृष्टि से 90 क्षेत्रो मं विमाजित किया गया है। प्रत्यक धमणदील पायालय म 3 से 9 तक न्यायाधीस होत है एव विवाद की सनवाई के समय कम से कम दो यायापीयों की उपस्थित अनिवास होती है। निकत सुवधानिक प्रश्ना से सम्बन्धित निवादो की सुनवाई 3 यायाधीशा की पीठ (beach) द्वारा की बाती है। जिला बायालय संधीय न्यायपालिका के सबसे छोटे बायानय है। इन्ह कवल प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, बद्यपि मंभी-कभी राज्या के यायालयों सं सन्ब िधन विवाद इनके विचाराथ भेज दियं जाते हैं। सवधानिक मामला सम्बाधी अपीलें इन पायालया सं सीधे सर्वाच्च पायालय मं की जा सकती हैं। जिला पायालयों म क्म से कम एक और अधिक से अधिक 6 यायाधीश होते है। कम जनसंख्या वाले राज्या म एक जिला यायालय होता है और अधिन जनमध्या वाले राज्यों में अधिक जिला यायालय होते हैं। उदाहरण के लिए, यूयान राज्य में 4 जिला यायालय हैं। भ्रमणशील संघीय यायानय पुनरावेदनीय क्षेत्राधिकार सम्पन्न होत है । 1948 ई तक इन यायालया को (सर्किट) अमणशील अपी नीय यायालय की सजा दी जाती यी लेकिन इसी वय से इंड संघीय पुनरावेदनीय यायालय (Federal Courts of

Appeal) के नाम से पुकारा जाने लगा है। सवशयम इन यायालयों की स्थापना 1891 ई म सर्वोच्च यायालय के पुनरावेदनीय (appellate) कायभार का कम करते के लिए की गयी थी। इन यायालया द्वारा पहले की माति अव स्थान स्थान के दौरे नहीं किये जाते हैं अपितु वे बहुत ही कम दौरे करते हैं। इह सधीय व्यापार आयोग (Federal Trade Commission), राष्ट्रीय थम सम्बच मण्डल (National Labour Relations Board) एव अप विविच राष्ट्रीय सस्थानों के निणया के विरुद्ध अपीलें सुनने का अधिकार प्राप्त है। सधीय पुनरावेदनीय यायालयों की तुलना में जिला यायालय अपेकाङ्कृत अधिक व्यस्त रहते हैं।

उपरोक्त तीना प्रकार के संघीय "यायालय संवधानिक "वायालय (Constitutional Courts) कहे जाते हैं क्योंकि ये सविधान के आधार पर निर्मित है । इनके अतिरिक्त विशेष यायालय है। इन विशेष यायालया की स्थापना समय समय पर काँग्रेस द्वारा की गयी है। विशेष यायालय तीन प्रकार के होते हु प्रथम, दायो का मायालय (Court of Claims), द्वितीय, संयुक्त राज्य का सीमा शुल्क पायालय (Uni ted States Customs Courts), ततीय, सीमा शुल्क एव एकस्व पुनरावेदनीय "याया-लय (United States Courts of Customs and Patent Appeals) । दावो के यायालय (Court of Claims) की स्थापना 1855 ई मे की गयी थी। इस याया लय को शासन के विकद धन सम्ब धी दावी (claims) को सुनने का एकाधिकार प्रदान किया गया है। इसके पून शासन के विरुद्ध धन सम्बाधी दावो की सुनवाई करने वाला कोई यायालय नही था। 1926 ई मे दूसरा विशेष यायालय स्थापित किया गया । यह सयुक्त राज्य का सीमा शुल्क (कस्टम) यायालय है एव वस्तुओं के सीमा शुल्क सम्ब भी विवादा का निणय करता है। तीसरा यायालय सीमा शुल्क एव एकस्व अपील यायालय सीमा शुल्क सम्बन्धी विवादा का पुनरावेदनीय न्यायालय है। यदि कोई आवि प्लारक यह अनुभव करता है कि वाणिज्य विभाग न उसके आविष्कार का अनुचित रूप स एकस्व (patent) किया जाना अस्वीकृत किया है तो इस यायालय मे वह विवाद को निणय हेतु प्रस्तुत कर सकता है। इसके अतिरिक्त अय विशेष यायालय भी है। इन विशेष यायालया का काय उन विधिया के क्रिया वयन म प्रशासन की सहायता करना है जो काग्रेस द्वारा अपनी निहित शक्तिया या प्रदत्त शक्तिया के अधीन निर्मित की जाती हैं। वे सघीय यायालय उपरोक्त विजत सबैधानिक यायालयो स मिस्र है। इनकी स्था पना काँग्रेस अपनी विधायनी शक्ति के अधीन करती है, न कि सवधानिक प्रदत्त शक्तियो के आधार पर। इन यायालयो के यायाधीशो को निश्चित पदाविब के लिए नियुक्त किया जाता है तथा पदच्युत करने के लिए सर्वधानिक यायालया की भाति उन पर महामियोग लगान की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इन "यायालया ने निषया ने निरुद्ध अपीले सधीय सबैधानिक यायालयो म की जा सकती हैं। अमेरिकी सविधान के अनुच्छेद 3 व द्वारा सघीय यायपालिका की व्यवस्था की गयी है। सघीय यायपालिका की अपन

826 | आधुनिक द्वासनतन्त्र

क्षेत्र म व्यवस्था एव कायपाविका क समान ही (coordinate) व्यक्तिया प्राप्त है। स्विधान में कोई विस्तात उपय च नहीं किया गया है अपितु केवल यही उद्दित्तविक है होंगी जिनकी स्थापना एक सर्वोच्च यायालय एव व य अधीनस्य यायालय में निहंत होंगी जिनकी स्थापना समय समय पर कांग्रेस के बारा की नायेगी 11 वत सिवान सर्वोच्च यायालयों की नायस्थकतानुसार स्थापना तथा अधिकार कांग्रेस को प्रयान तथा यायालयों के यायायायों की संख्या निर्धारित करने स्थापना तथा है।

स्मरजीय है कि परिताय के सविधान (Articles of the Confederation) म राष्ट्रीय यायपालिका की कोई व्यवस्था नहीं थी। परिसय काल म समी पाणिक विवादा का निषय राज्या के यायालयो द्वारा किया जाता था। प्रत्येक राज्य की अवनी पयक एव स्वत-न याय व्यवस्या थी। इस काल म राज्यों के यायालयों द्वारा परस्पर विरोधी निषय दिये जाते थे। फलस्वरूप अस्थिरता एव अनेक प्रकार की जिटिलताएँ उत्पन्न हो जाती थी। परिसय म राष्ट्रीय यायासय का अमाव हैमिल्टन की हिट्ट में उसमा प्रधान दोप था। हैमिस्टन का कपन या कि विधियों को क्रिया-वित करने वाले पायालय के अमाव म विधि का कोई मुल्य नहीं होता है वह मृत पत्र के सहस्य है । अन अमेरिकी सविधान नियाता ऐसी याय व्यवस्था की स्वापना के लिए प्रयत्तवील थे जिससे कि परिसयकासीन अराजकवा एव अस्पिरता की पुनरा-वित न हो एव स्थायी शासन की स्थापना हो सके। इसके अतिरिक्त 1789 है के अमेरिकी सविधान द्वारा सभीय व्यवस्था को अपनाया गया था। अतः सपीय धासन एव राज्या के मध्य विवादों का निषय करने हेतु एक स्वतंत्र निकाय जो निष्णा पच की भूमिया निमा सके, का होना प ताओं ने सर्वोच्च यायालय का सीपा ह दायित्व राजनीतिक हृष्टि स राज्या न . था । यह दायित्व सविधान निर्मा सविधान लिखित है। उसकी मापा एव ो के निणयो ना प्रस्ता का उठना स्वामातिक । राज्यां व ो था। अमरिकी या वायित्व सीपा/ निणय दिय जात ल्या सम्ब भी नही हाता । जमि ो व्याख्या के निर्माण क लिए अनिवायता थी ।

^{1 &#}x27;Judicial power is inferior courts as establish' —Artic W B Munro, 194

सर्वोच्च न्यायालय का सगठन

समेरिकी सर्वोच्च यायालय की स्थापना 1789 ई म काग्रेस की विधि के द्वारा की गयी थी। प्रारम्म में मुख्य यायाधीश सिह्त इस यायालय में केवल 6 यामाधीश थे। स्मरणीय है, अमेरिकी सिवधान द्वारा 'यायाधीशों की सरया निश्चित नहीं की गयी है। वह समय-समय पर परिवर्तित होती रही है। 1801 ई म यायाधीशों की सरया 5, 1807 ई म 7, 1837 ई म 9 एव 1863 ई म 10 थी। सन 1866 म इसे कम करके पुन 7 कर दिया गया था। 1869 ई में इसे बढाकर 9—एक मुख्य यायाधीश एवं 8 अप यायाधीश —िवश्चित कर दिया था। उस समय से यही सख्या चली आ रही है।

सर्वाच्च यायालय के यायाधीशो की नियुक्ति राष्ट्रपति हारा सीनेट के अनु-मोदन से की जाती है। यायाधीशा की नियुक्ति के सादम में 'सीनेट का शिष्टाचार नहीं निमाया जाता है। सीनेट ने याया बीदों की नियुक्ति सम्बन्धी राष्ट्रपति की सभी सिफारिशो को स्वीकार भी नहीं किया है। 1930 ई म राष्ट्रपति हूनर के द्वारा की गयी जॉन पाकर की नियुक्ति को सीनेट ने उनके श्रम सब विरोधी हण्टिकीण एव नीग्रा विरोधी मावना के कारण अस्वीकृत कर दिया था। राप्ट्रपति यायाधीशो की नियुक्ति करते समय केवल विधिक योग्यता को ही घ्यान में नहीं रखता अपितु क्षेत्रीय एव धार्मिक भावनाओं तथा राजनीतिक विचारों को भी ध्यान में रखता है । सर्वोच्च यायालय के यायाधीशा को सदाचरणपय त काल के लिए नियुक्त किया जाता है। 10 वस तक यायाधीश के पद पर काय कर चुकने तथा 70 वस की अवस्था प्राप्त करने पर यायाधीशा को स्वेच्छा स पद से त्यागपत्र देने की स्वत तता है पर तु महामियोग द्वारा उह पद से पृथक किया जा सकता है। अभी तक केवल एक बार 1804-5 ई म समुझल चेस नामक यायाधीश पर महाभियोग लगाया गया है और वह मी असफल रहा था। यायाधीको को समुचित बेतन दिया जाता है। अमेरिकी मुत्य यायाधीश का कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं हैं। वह केवल यायाधीशा की अध्यक्षता करता है।

सर्वोच्च यायालय का वप म केवल एक ही सर अक्टूबर के प्रथम सोमवार से जून के मध्य तक होता है। विवादों की सुनवाई महीने के एक पहायाडे म मगल-बार, नुपवार, वहस्पतिवार एव शुक्रवार को होती है। श्वनिवार को सभी मामापींद्रा आपस में मिसकर विवादा पर विचार विमध करते हैं और सोमवार को निषय सुनाये जाते हैं। निषय बहुसत के कियं जाते हैं। दूसरा पखवाडा यायाधीश अध्ययन पद निषय खिलों म ब्यतीत करते हैं। निषय से अबहुसति रखने वाले यायाधीश अपना विमत (dissenting judgment) दे सकते हैं। क्षेत्र म व्यवस्था एव कामपालिका के समान ही (coordinate) सिक्तमा प्राप्त हैं।
मिवधान में कोई विस्तन उपबन्ध नहीं किया गया है अपितु केवल यही उदिलेखित है
कि 'यापिक बिक्तमा एक सर्वोच्च न्यायालय एवं अप्य अधीनस्थ यायालया म निहित्र
होगी जिनसी स्थापना समय समय पर कांग्रंप के द्वारा की जायेगी। अत सविधान
दारा संधीय यायपालिका ने अप्य यायालयों की आवश्यकतानुसार स्थापना तथा
सर्वोच्च यायान्य सहित संधीय यायालयों के पायाधीशों की संस्था निर्धारित करने
का अविकार कांग्रेस को प्रदान किया गया है।

म्मरणीय है कि परिसंघ के सविधान (Articles of the Confederation) में राष्ट्रीय यायपालिया की कोई व्यवस्था नहीं थी। परिसंध काल म समी पायिक विवादा का निषय राज्या के यायालयो द्वारा किया जाता था। प्रत्येक राज्य की अपनी पथक एव स्वत व याय व्यवस्था थी। इस काल मे राज्या के यायालया द्वारा परस्पर विरोधी निणय दिय जाते थे। फलस्वरूप अस्थिरता एव अनेक प्रकार की जटिलताएँ उत्पत्न हो जाती थी। परिसच म राष्ट्रीय यायालय का अमाव हैमिस्टन की हरिट म उसका प्रधान दोए था। हैमिल्टन का कथन था कि विधियों को किया वित करने वाले यायालय के जमाव मे विधि का कोई मूल्य नहीं होता है, वह मृत पत के सहस्य है। अन अमेरिकी सविधान निर्माता एसी न्याय व्यवस्था की स्थापना वे लिए प्रयत्नदील थे जिससे कि परिसधकातीन अराजकता एव अस्पिरता की पुनरा-वृति न हा एव स्थायी शासन की स्थापना हो सके। इसक अतिरिक्त 1789 ई क अमेरिकी सविधान द्वारा सधीय व्यवस्था का अपनामा गया था। अत संघाय धासन एवं राज्या के मध्य विवादों का निषय करन हेतु एक स्वत व निकाय जा निष्पक्ष पच की सुमिका निसा नके, या होना परमावश्यक था। यह वायित्व सविधान निर्मा-ताआ ने सर्वाच्च यायालय को सापा है। संधियों सम्बंधी विवादों के निजया ना वायित्व राजनीतिक हर्ष्टि से राज्या के यायालया का दना उचित नही था। अमरिकी सविधान निवित है। उसकी मापा एव विभिन्न उपबाधा के अब एव व्यास्था सम्बाधी प्रश्नों का उठना स्वासाविक है। राज्यां के यायालया को यदि सविधान की व्याख्या का दायित्व सीधा जाता तो प्रत्येक राज्य के "यायालय द्वारा मिग्न-मिन व्याख्या सम्बन्धी निगय दिम जाते । इससे गतिरोध एवं अराजवता का उत्पन्न हो जाना अस्वामाविक नहीं होता । अमरिनी सविधान निमाता जिस यायपूर्ण समाज एव पूर्ण राष्ट्रीय एकता क निर्माण न लिए प्रतसनस्य थे, उस दृष्टि स सर्वोच्च यायालय की स्वापना एक अभिवाधना भी ।

i 'Judicial power will be vested in one Supreme Court and such inferior courts as the Congress may from time to time ordain and establish "-Article 3 The Constitution of the United States W II Murro 1947 pp 95 96

सर्वोच्च न्यायालय का सगठन

अमेरिकी सर्वाच्च यायालय की स्थापना 1789 ई म काग्रेस की विधि के द्वारा की गयी थी। प्रारम्भ मे मुख्य यायाधीश सिह्त इस यायालय मे केवल 6 यायाधीश थे। स्मरणीय है, यमेरिकी सिवधान द्वारा यायाधीशों की सरया निश्चित नहीं को गयी है। वह समय-समय पर परिवित्तत होशी रही है। 1801 ई म यायाधीशों की सख्या 5, 1807 ई म 7, 1837 ई में 9 एवं 1863 ई में 10 थी। सन 1866 म इसे कम करके पुन 7 कर दिया गया था। 1869 ई में इसे बढ़ाकर 9—एक मुख्य यायाधीश एवं 8 अन्य यायाधीश —िविच्त कर दिया था। उस समय से यही सख्या चली आ रहीं है।

सर्वाच्च यायालय के यायाधीशा की नियक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट के अनु-मोदन से की जाती है। यायाधीशों की नियुक्ति के सदम में 'सीनेट का शिष्टाचार' नही निमाया जाता है। सीनट न यायाधीयों की नियुक्ति सम्बंधी राष्ट्रपति की सभी सिफारिशा को स्वीकार भी नहीं किया है। 1930 ई में राष्ट्रपति हुनर के द्वारा की गयी जॉन पाकर की नियक्ति को सीनेट ने उनके श्रम सघ विरोधी हिष्टकोण एव नीम्रा निरोधी भावना के कारण अस्वीकृत कर दिया था। राष्ट्रपति यायाधीशी की नियुक्ति करते समय केवल विधिक योग्यता को ही घ्यान में नही रखता अपितु क्षेत्रीय एव घामिक मावनामा तथा राजनातिक विवारो को भी ध्यान मे रखता है। सर्वोच्च यायालय के यायाधीशा को सदाचरणपय त काल के लिए नियुक्त किया जाता है। 10 वप तक यायाधीश के पद पर काय कर चुकने तथा 70 वप की अवस्था प्राप्त करने पर यायाधीशों को स्वेच्छा से पद से त्यागपत्र देने की स्वत नता है परतु महानियोग द्वारा उह पद स पृथक किया था सकता है। अभी तक केवल एक बार 1804 5 ई म समुजल चेस नामक यायाधीश पर महाभियोग लगाया गया है और वह भी असफल रहा था। यायाधीशो को समुचित वेतन दिया जाता है। अमेरिकी मुख्य यायाधीश को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। वह केवल यायाधीणा की अध्यक्षता करता है।

सर्वोच्च यायालय का वय म कथल एक ही स्तर अक्टूबर के प्रथम सोमवार से जून के मध्य तक होता है। विवादो की सुनवाई महीने के एक पश्चवाड़ में मगल-वार, पुपवार, पुहस्पितवार एव शुक्रवार को होती है। श्चितवार को सभी मायाबीश आपस म मिनकर विवादा पर विचार विमश करते हैं और सोमवार को निणय सुनाय जाते है। निणय बहुमत से किये जाते है। इसरा पखवाडा बायाधीश अध्ययन एवं निणय लिखने म व्यतीत करते हैं। निणय से असहमति रखने वाले यायाबीश अपना विमत (dissenting Judgment) दे सकते हैं।

सर्वाच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार'

सर्वोच्च 'यायालय को मौलिक एव पुनरावेदनीय (appellate) दाना हा प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त है ।

मौलिक या प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अत्वगत निम्नलिखित विवाद आते हैं

- (1) राजदूती, अंच सावजनिक मीत्रयो एव राजनयिक अधिकारियां (Public Ministers and Consuls) से सम्बन्धिन विवाद ।
- (2) ऐसे समस्त विवाद जिनम नाई एक राज्य एक पक्ष म हो। अत वे सभी विवाद जिनमें मयुक्त राज्य अमेरिका एक पक्ष मे हो दो या अधिक राज्या क मध्य विवाद, एक राज्य तथा विदेशी राज्य एव नागरिक तथा प्रजाजना के मध्य विवाद सर्वोच्च यापालय के मौलिक क्षेत्रामिकार के अस्तत्त आत हैं।

इनके अतिरिक्त व य सभी निम्माकित विवाद मर्वोच्च यायालय के पुनरा-वेदनीय क्षमाधिकार के अधीन हैं।

- (1) सिवधान के प्रधीन विधि एव सुनीति (equity), समीय विधिया एव सयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सम्पादित सिंधवी एव प्रविच्य में की जाने वाली सिधया सम्बाधी विवाद ।
 - (2) नौ मैना एव जलीय यातायात सम्ब नी विवाद ।

(3) विभिन्न राज्यां के नागरिकों के मध्य विवाद, अप किसी राज्य के अनु दान के सम्बन्ध में एक राज्य म विभिन्न नागरिका के मध्य विवाद ।

सर्वोच्च मामालय को उपरोक्त सभी विवादों में विवि तथा तथ्या (law and facts) ने सम्बाध म पुनरावदनीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। परस्तु निम्न मधाय यायालया के निषया अपका राज्यों के उच्च वायालया के सभी निषया के विवद्ध सम्बाधित पक्षा का स्वेच्छापुक प्रवोच्च न्यायालय म पुनरावदन की मुविधा प्राप्त कर्तु है। सम्बाधित पक्षा को राज्यों के यायालया क विवद्ध निम्न अस्पालों म कव्य अपील का अधिकार प्राप्त है (!) उच्च न्यायालय द्वारा जब किसी ऐसी राज्य विधि को वध उहुराया गया हो जो सधीय सविधान या कांत्रस की विधि या समुक्त राज्य अमरिका द्वारा सम्पादित किसी सिध वे विपरीत हो, या (2) राज्या क उच्च यायालय न किसी सभीय सीच वािष ने विवादा कर ही सीधित है पर पुरायालय का पुनरावदनीय योगाविष्य म विधि मा सीच सवींच्च यायालय यायालय स्थान की अनु भित्र प्राप्त कर वे वािष कर विवादा कर ही सीधित है पर पुरायालय का प्रवाद वािष्ठ विवादा म सवींच्य यायालय य अपील की अनु भित्र प्राप्त कर दी जाती है उन विवादा म सवींच्य यायालय य स्थीन की अनु भित्र प्राप्त कर दी जाती है उन विवादा म सवींच्य यायालय म सीचे व्यक्ति हो

² Section 2, Article 3 of the Constitution of the United States, 'A Government by the People' U S I S Publications, p 98 and Munro op at, pp 99 113

सकती है। सर्वोच्च यायालय के पुनरावेदनीय क्षेत्राधिकार को नियमित करने का अधिकार कांग्रेस को प्राप्त है।

सर्वोच्च यायालय को स्वविवेक स उरप्रेषण आदश (certiorari orders) जारी करके निम्न यायालया से विवाद को अपने समक्ष विचाराय मँगाने का भी अधि कार है।

अमेरिकी सर्वोच्च यायालय सारतीय 'यायालय की मांति परामदादायी काय सम्मादित नहीं करता । यायाधीश माशल न कायपालिका का किसी अमूल प्रस्त या विषय पर परामदा देने से इकार कर दिया था। उनका मत था कि सर्वोच्च 'यायालय हारा राष्ट्रपति को परामदा देन का अय यह है कि 'यायपालिका कायपालिका के अधीरिक सर्वोच्च 'यायालय हारा परामदा देन शक्तिरक्त सर्वोच्च 'यायालय हारा परामदा देना शक्ति-मृथदकरण के मिद्धात के भी विपरीत है।

मौलिक क्षेत्रधिकार सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च यायालय मे कम ही आते है। राजनिक अधिकारी (diplomatic personnel) अन्तर्राष्ट्रीय विधिके नियमा के कारण प्यायालय के क्षेत्राधिकार के अवीन नहीं हाते है। राजनिक उ मुक्तियों (diplomatic immunities) से जबित कुछ निम्म राजनिक अधिकारियों पर अन्य सधीय यायालयों म मुकदमें बताये जा सकते हैं जिनको समवर्ती क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। 1925 ई के सुधारों के परचात सर्वोच्च यायालय में पुनरावेदनीय विवादों का आना कम हो गया है। सर्वोच्च यायालय के पुनरावेदनीय विवादों का आना कम हो गया है। सर्वोच्च यायालय के सुमी अधीनस्य सधीय यायालयों के कार्यों के निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है।

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय एव न्यायिक पुनरीक्षण

व्यवस्पिषिका एव कायपालिका के कार्यों के सविधान के विपरीत होन की वधा म यायालयों को उन्हें नविधानिक घोषित करने की शक्ति होती है। यायालयों के इस अधिकार को यायिक पुनरींशण की शक्ति या अधिकार कहत हैं। इस कभी कनी पायिक निर्वेषाधिकार (Judicial Veto) की भी सज्ञा वी जाती है। वस के अनुसार सर्वेधानिक आधार पर घासन के अय अधिकरणा के कार्यों की अवधानिक घोषित करने की सर्वोच्च यायालय की शक्ति को यायिक पुनरींशण कहते हैं। यरत शब्दों में पायिक पुनरींशण से अब विधिया एव शासन के कार्यों का सविधान की व्यवस्था के आधार पर यायालय झारा परीक्षण है। अमेरिकी सर्वोच्च यायालय को प्रायक यायिक पुनरींशण के अधिकार से विटिश ससद की सर्वोच्चता की मीति पायिक सर्वोच्चता (Judicial supremacy) का अम उत्पन्न नहीं होना चाहिए। कभी-कमी

Judicial review is 'the power of the highest court of jurisdiction to invalidate, on constitutional grounds the acts of other govern mental agency within that jurisdiction' —Berth, L. P. The Constitution & The Supreme Court, 1962 p. 16



आदेप जारी किय ये परन्तु मारवरी वी नियुक्ति सम्यन्धी उक्त आदेश की भेजन के पूत ही राष्ट्रपति एडम्म का रायकाल समाप्त हा गया था । नवीन राष्ट्रपति जैफरमन एव सचिय महीमन ने मारवरी को नियुक्ति सम्बंधी आदेश को भजना अम्बीकार नर दिया । इस पर मारवरी न सर्वोच्च यागालय स राप्ट्रपति के विरुद्ध परमादेश जारी गरने की प्राथना की । इस विकाद म 1803 ई म निषय दते हुए मुख्य वाया धीरा माराल न कहा था रि "मारवरी को अपनी नियक्ति सम्य थी आदेश प्राप्त करन **रा अधिकार है परातु सर्वोच्य यायालय को यह अधिकार नही है कि वह मारवरी** को नियुक्ति मन्याधी आदस दिय जान हेतु परमादश जारी वरे। इसका कारण यह है कि 1789 ई का जुडीशियल एक्ट सविधान व अनुच्छेद 3 के विषरीत है क्योंकि इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार की अमुच्छेद 3 म उल्लि सित क्षेत्रापिकार की तुलना व वृद्धि की है। अत उक्त अधिनियम अवधानिक है। पायाधीन माराल का यह तर्क या कि "यह निश्चय करना निस्स देह याम विमाग का क्षेत्र एव दायित्व है कि विधियाँ क्या है।" इसके अतिरिक्त सविधान लिखित तथा देश की सर्वोच्च विधि है और कांब्रेस की सामा य विधिया स श्रेष्ठ है। अत "यागा-धाशा का यह नतम्य है कि वे सविधान का आदर करने हुए विधियों को जिथायित करें। यदि वृश्विस की कोई विधि सविधान की किसी धारा का अंतिक्रमण करती है ता वह असवधानिक है एव स्पत ही प्रमावहोन हा जाती है। इस निषय न पूरी तरह यह निश्चित कर दिया कि यायपालिका का यह अधिकार एवं कतक्य है कि वह विधानसण्डल एव कायपालिका के कार्यों की सविधान की घाराआ की कसीटी पर कस कर उनकी वधानियता के सम्बाध म निर्णय दे और यदि कोई विधि या नाय सविधान भी किमी घारा क प्रतिकृत है, तो उस अवैध घोषिन कर दे।

इसी तरह का एक अय महु बपूण विवाद मकलाउन बनाम मेरीलण्ड (1819) (McCulloch v Maryland, 1819) है। 1791 ई मे कीग्रम न कुछेक राज्या के तीय पिराध क वावजूद भी वक स्थापना सम्बन्धी आदेश पारित किया था। इस आदग क अनुतार गान्द्राम बैंक को दशक्यांची क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया था एक स्मि ने वाधार पर प्ररीत कर राज्या के बाल्टीमोर नामक नगर मे राष्ट्राम बैंक की एक शाल्या स्थापित भी की गयी। 1818 ई मे नेतिलच्च राज्य वे अपने राज्य में प्रचालत तथा जन समस्त पत्रमुद्रा पर स्टाम्प कर तथाने की घोषणा की जो मेरीलेच्च की वकी या उनकी शाखाबा द्वारा राज्य में आदेश के नमय जारी किये गये थे। सधीय बक की बाल्टीमार शाखा ने स्टाम्प कर देना अस्वीकार कर दिया। इस पर मेरी

^{8 &}quot;It is emphatically the province and duty of the judicial department to say what the law is If two laws conflict each other the courts must decide on the operation of each "Mathury v Madison (U S 1) S C (1808) Granch 137



1935 ई मे सर्वोच्च यायालय ने राष्ट्रीय औद्योगिक पुनव्यवस्था अधिनियम, 1933 ई (National Industrial Recovery Act, 1933) को उस सीमा तक अवधानिक उहराया था जहां तक कि विधेयक का राज्यों के उद्योगों से सम्बन्ध था। उक्त एकट राष्ट्रभति रूजेटल के यू ढील कायक्रम का अग था। इसके अतर्गत राष्ट्रभति एक विध्यापक को क्यापक की गया थी। इस पर यह आपत्ति की नियम निर्माण की ख्यापक इतिचया कियम निर्माण की विध्यायी शक्ति इसता कर दी गयी कि कोब तस्तुत सविधान हारा काय्याविका को नियम निर्माण की विध्यायी शक्ति इसते पक्ष ने इसे अधीनस्थ विधि निर्माण वताया और विधायी शक्ति का प्रविक्तरण नहीं माना। सर्वोच्च यायालय ने सवसम्मति से इस व्यवस्था को विधायी शक्ति का प्रविक्तरण (delegation) मानते हुए अधिनयम को असर्वधानिक (unconstitutional) धोषित कर दिया था।

अमरिकी सिवधान के पाँचवे सन्नोधन द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि िसती व्यक्ति को विधि को उचित प्रतिया (due process of law) के बिना जीवन, स्वत तता एक सम्यक्ति से विचित नहीं किया जायेगा। यह सवीधन विश्व रूप में सबीय शासन से सम्बध्धित है। 14वें संशोधन द्वारा राज्यों की सरकारों पर भी यह प्रतिवास कागा गया है। इस सशीधन का सक्ष्य स्वत न नागरिकों के रूप में नीयों होगों के अधिकारों की रक्षा करना था। इसके परचात अनेक विवाद सर्वोच्च पायान्त्व के समक्ष प्रस्तुत होते रहे हैं और उसके जीवन, स्वत नता, सम्पत्ति, व्यक्ति एव विधि की उचित प्रतिया की ब्यास्था करके राज्यों एवं के दीय सरकारों के कायसेन को आध्वपता कर रूप सीमित किया है। स्मरणीय है, 1870 ई एवं 1880 ई म राष्ट्रपति एवं कांग्रेस के कायों का, जिनके द्वारा नीमा चारि के लोगों की रक्षा के प्रतिवाद किया है। स्वरणीय है, विस्त के लोगों की रक्षा के प्रयत्त किये गये थे, सर्वोच्च यायालय ने अवैधानिक उद्दराया था।

सर्वोच्च यायालय न अभी तक 80 विवादों में काग्रेस की विधिया एव उनसे सम्बिधत विभिन्न उपव भी को जवधानिक धीपित किया है और उनम सं भी केवल 8या 10 विधिया को पूरी तरह अवधानिक उहराया है। स्मरणीय है, कियेस न 1789 ई के पश्चात करीब 70 हजार सं भी जीधक विधिया पारित की है। करीब 30 हजार विध्या की सम्बिध्य है। स्पष्ट है कि यायिक पुनर्रोक्षण का सम्बध्य है। स्पष्ट है कि यायिक पुनर्रोक्षण का सम्बध्य यहाँ है। क्रा है। क्रा है जिल्ला विधियों से स्वीधित है। क्रा है। क्रा है कि यायिक पुनर्रोक्षण का सम्बध्य यहाँ थी से ही विधियों से ही रहा है, परन्तु अमरिकी राजनीतिक जीवन में इसका अमरवक्ष रूप से स्थापक प्रभाव पढ़ा है।

सर्वाज्व न्यायालय के "यायिक पुनरीक्षण का सम्ब ध के द्र एव राज्या के क्षेत्र एव अधिकारी तथा मौलिक विधिकारी से है। सर्वाज्व यायालय न वाणिज्य उपब ध (Commerce Clause) की व्याख्या तथा निहित शक्तिमा के सिद्धात नो विनसित

¹³ Schechter Poultry Corporation v U S, (1935), 295 U S 495

करके संघीय शासन की शक्तिया का असाधारण विकास क्या है और इस प्रकार साँध 836 | आधुनिक शासनत व धान को विकसित होन म योग दिया है। 18वी सदी क कृषि अब व्यवस्था प्रधान समात्र के लिए जो सविधान निमित्त किया गया था उसे सवधा मिन्न परिस्थितिया इ अनु कूल दालन का सराहनीय काय सर्वोच्च यायालय द्वारा किया गया है। संघीय वैठ हो कर लगाने प्रहण देने एवं कथिल द्वारा मूल्या की निर्धारित करने की पत्तिया हा विकास सर्वोच्च पापालय द्वारा सविधान प्रदत्त दक्तिया की व्यास्या क ही हाए सम्भव हो सका है। विदेशी राज्या एवं अन्य राज्या वे मध्य वाणिज्य (Commerce) सविधान क अनुसार विशेष के क्षेत्राधिकार म है। सर्वोच्च वावालय र इसी पार्टि व अतगत कोंग्रेस द्वारा पारित सभी अंत राज्यीय एवं विद्यो ध्यापार सम्बंधा ्र ज जना जाकर कारा नारास राजा जा संस्थान प्रणाचन । ज्यार प्रणाचन हो निवास एक आपार रत, तार रिडया वामुयान एवं जलपात डारा विया गया हो । उपरावत उस्लिसित भेक्साडब प्रकृतिक प्रवाद के द्वारा निहित वास्त्रिया के मिद्धा त की स्यापना को गया थी। सामाधीम मामल र जपन निषय म इस सम्बंध म बहु। है श्लासत की श्लिती नामानाम नाताम । अपन नामान न ६७ छन्न न न नशः छ । तामा ना नातामा सीमित हैं और उसकी दासिया वा अतित्रमण ही निया जा सकता। परपु हमारा जाराज्य । २ जार प्रतान वास्तान ना जायानात । १९ १५ वर्ष वा वा वा वा सामित है विस्ति सामित के स्वस्थ और म राष्ट्रीय विद्यासमझ्य का विश्व से बाद सी क्षेत्र प्राचनात्त्र रचरच अन्य प्राचन रचना स्वाप्त प्राचन र प्राचन प्रा नियारित महान् वतस्या वा अधिकाधिक जानत्यामाथ पूप किया जा नक। सर्वाच्च न्यायालय एव मीलिक अधिकार

ममुक्त राज्य अमरिका क सर्वाक्त वातालय न ध्वालिया न मोतिह अधिकारा भपुषा प्रश्नित अनारणा क सम्बद्ध प्रश्नाति में स्वाप्त मान्य स्वयं प्रश्नित स्वयं समयं समयं समयं स्वयं स्ययं स्वयं स्ययं स्वयं पुर परिवर्गित होति देती है। 1937 इ. व. पूर्व गर्दाध्य वाचा व व भरा अधिका : हारात सं मानस्य व असिकार का द्रां का प्रदान हिया था। पर रेटाक तंत्रीय गर्वास्य याचा त्व व्यक्तिय अधिकाश का र ॥ क रिष् अधिक किन्द्र प्रशान होता है तथा सम्मीत की मुक्ता म समावन व्यापात्म नायन एवं व्यापता के अपिहार हो के राज्य जनसम्बद्ध कर स्टार्ट है। श्रवसाय है सरियान के हैं वे प्रवाह है स्टापित है। व्यक्ति मेर्ट व वह स्टार्ट है। श्रवसाय है सरियान के हैं वे प्रवाह है वे स्टापित है। मानक गर करने के पासना जांच विधि की प्रतिकृतिकता (due proces of law ह दिश्व कोई जीवक श्रमाना जाना निषय है और अमेरिकी नागरिक क भवाभिकार की राष्ट्र एवं रच व दि भग क वाधार पर शाधित वहीं दिया । क स्वतान्त्रकार कर राज्य के स्वतंत्रक स्वतंत्रक स्वतंत्रकार के स्वित्रमा स्वतंत्रकार के स्वतंत्रमा स्वतं रहरू भोरीचार राज्य को शहर करता संयोध के गर्न को नहें हो रहशा गर्न हमा गर्न हमा है है

¹⁴ Maritall C. I is if (and c Mary'red (tab)

नारा ने नार्यों ने अधिक है। 1938 ई के परचात धार्मिक स्वतायता सम्याधी अनेक विवादा म सर्वोच्च यामालय ग यह निषय दिन हैं कि नगरा एव राज्या के द्वारा धार्मिक स्वत प्रता का अतिश्रमण किया गया है। सर्वोच्च यामालय न अपन एक निष्प्र म कहा है कि न तो राज्या की मरपार्ट और न संधीय सरकार ही चव की स्वापना कर सस्ती है और न य ऐसी विधिया पारित कर सकती हैं औ एक तथा अनेक धर्मों की सहायता और एक धर्म को दूसर सं प्राथमिकता दती हा। सर्वाच्च यामालय के एक दूसर निष्य के अनुनार राज्या के विधायता स्वाप्तिन धर्मी के प्रतिनिधिया को धिश्वा के दौरान पार्मिक विद्या नहीं ही जा स्वयंची है।

विचार एव नापण, धम एव समुदाय की स्वतात्रताओं के सम्बाध म सर्वोच्च यापालय का विगत 20 वर्षा म यह दृष्टिकीण रहा है कि इन स्वत त्रतामा म हस्त-धेप एव इन्ह सीमित करन वाली विधिया का उसी अवस्था म अवधानिक घोषित किया जाना चाहिए जबनि स्थप्ट एव तारकालिक सावजनिक सुरक्षा हेत् हस्तक्षेप की अनिवायता सिद्ध न हाती हो । यायाधीश होम्स (Justice Holmes) इस सिद्धा त क सूत्राधार थे। उनक अनुसार 'इस स्वत त्रताजा को सावजनिक हित म ही सीमित करने का स्पष्ट भौचित्य हो सकता है। ' अत यह मौतिक अधिकार अधिक सुदृढ नाधार पर आधारित है। उदाहरणाय, 1952 ई म सर्वोच्च यायालय न चलचिता क माध्यम से अभिव्यक्ति (expression) को भाषण एव प्रेस की स्वतन्त्रता के अलगत स्वीकार निया या। सर्वोच्च यायालय क अनेव निणयो का सम्याध रगभेद से है। सर्वोच्च यायालय के निणया क फनस्वरूप अमरिकी समाज म नीवी जनता की स्थिति म सुधार हुआ है। अमरिका म काल गोर-- स्वेत अमरिकी एव नीयो जनता के मध्य भेद व्याप्त है। नीग्रो जनता कं लिए समाज म पृथक होटल, विद्यालय आदि है। नीग्रो के लिए इस प्रभार की पृथक व्यवस्थाया को सर्यांच्च यायालय ने अवैधानिक ठहराया हैं। "स्कूना म नीमा वालका के लिए पृथक व्यवस्था का अब सर्वोच्च पायालय की दिष्ट म इन बालका का समान सक्षणिक सुविधाओं से विचत कर देना है। "पृथकता एव समानता क सिद्धात के लिए एक साथ कोई स्थान नहीं है। पृथक शिक्षा सुविधाएँ निश्चय ही असमान होती है।" पृथकता की व्यवस्था विभेद को सिद्ध करती है, यह मत बाउन बनाम शिक्षा बोड नामक विवाद म सर्वोच्च यायालय द्वारा यक्त किया गया था। नीग्री स्वत त्रता एव मुक्ति कं इतिहास म यह निषय युगा तरकारी है। इसके पश्चात समुक्त राज्य अमेरिका म विधि द्वारा पृथकता की व्यवस्था का बस्तुत अ त हो गया है।

सर्वोच्च न्यायालय का महत्व

अमेरिकी सर्वाच्च यागालय ने अमरीकी राष्ट्र के विकास म महत्वपूण भूमिरा अदा की है। 1780 ई के दशक म लघु फूपि प्रधान समाज के लिए जो सर्विधान निर्मित किया गया था, वह वतमान अमेरिकी समाज (जो 13 के स्थान पर 50 राज्या का जोचोंगिक सम है) वे हिलो की पूर्ति कर रहा है। अमेरिका की जनसच्या म मी कई पुना बिंद्ध हो गयी है। वतमान परिस्थितियों के अनुकृत सिवधान को दालन म सर्वोच्च प्यासम्य का सराहतीम सीग है। सधीम दासन की सरिक्त्या में मी बंद हूँ है। यह सर्वोच्च प्यासम्य का सराहतीम सीग है। सधीम दासन की सरिक्त्या में मी बंद हूँ है। यह सर्वोच्च प्यासम्य द्वारा विकसित निहित्त अस्मित्रों के सिद्धा त' द्वारा ही सम्मय द्वारा है। सधीम वैक को कर लगाने, क्ष्म देने, कांग्रेस हारा मूल्या के पियो रित करने वा अधिकार इसी सिद्धा त का परिणाम है। मूल मर्वेशनिव व्यवस्था के अनुसार सम पी इकाइमां—राज्य-अधिका विवादी थी और केंद्र अपेकाइत कम जोर था। ते किन आज स्थित उत्तर वर्धी है। इसका श्रेम सर्वोच्च प्यासमय कि निगयों को है। वाणिज्य पारा सम्बंधी विवादी म सर्वोच्च व्यायालय ने अपेन निगया में वार्म को है। वाणिज्य पारा सम्बंधी विधादों को वैधानिक टहराया है, असे ही व्यापार रत्न, तार, रेडियो, हवाई जहान, जलपोत द्वारा किया गया है। सक्षेप में, सर्वोच्च प्यासलय ने संविधान को परिवर्तित परिस्थितिया के अनुकृत विकसित विया है। इसके अतिरिक्त मर्वोच्च पायालय सिवरात का सर- क्षम हो अपेकारों का जावच्च रक्त है और उत्तने व्यवस्थापिका के असितम्य के कामण के कामणातिका के विदान को वासकार की कामणातिका के असितम्य के कामणातिका के कामणातिका के विवाद की विवाद की रहा की है।

पर तु 19 की सदी एव 1935 है तक अमेरिकी धर्मोच्य "यायालय सप्यम सम के सम्मति सम्ब पी अधिकारा की क्या करता रहा था और माधारण जनता के अधिकारा की तुलना म सर्वाच्य नामान्य सम्मत्ति एव सम्मतिसातिया का गढ़ सिद्ध हुना था। इस काल ने सर्वोच्य नामान्य ने आय-कर, "यूनतम वेतन एव लाम के सीमित पत्थे सम्बन्धि विधियों को अवधानिक भीष्य-करते हुए दामता को दीवत उद्दरामा था। जासीचका का भत है कि सर्वाच्य नामान्य न प्रमतिसोत विधियों का विद्राध किया न प्रतिसोत विधियों का विद्राध किया न प्रतिसोत विधियों का विद्राध किया था। जासीचका का भत है कि सर्वाच्य नामान्य न प्रमतिसोत विधियों का विद्राध किया था। वस्ति हम काल म वह लोकत त्रीय कम स्विवादी अधिक था।

ह्रोगन, सास्की, लुई ह्रोडो एव एडम पुरस ने सर्वोच्च 'यायात्रय के 'यायिक पुनरींझण के अधिकार की तीव आलोचना की हैं। यायिक पुनरींसण की दाक्ति के कारण सर्वोच्च 'यायात्रय सुतीय सदन (Third Chamber) वन पमा है। यायात्रय को सिवारा नार्या होने के कारण 'यायायोदा ह्यू, (Hughes) क अनुसार सविधान की है जो 'यायाधीस उत्त कहते हैं। यायादार मंजकर न तो मही तम कहा हो की स्वाच्य हो सविधान है। " अमरिकी सर्वोच्च न्यायात्रय हो सविधान है।" अमरिकी सर्वोच्च न्यायात्रय ही सविधान है।" अमरिकी सर्वोच्च न्यायात्रय की अत्याचार (judicial tytanny) वी

^{15 &}quot;We are under a Constitution but the Constitution is what the judges say it is"—Hughes, cited by A C Kapoor Select Constitutions, 1965, p 357

¹⁶ The Supreme Court II the Constitution '-- Justice Frankfurter, cited by A C Kapoor op cit, p 357

सजा दी गयी है। इस अत्याचार का एक बढ़ा कारण यह है कि यायाधीश अपने को परिवर्तित सामाजिक परिस्थितिया एव तदजनित आवश्यकताओं के अनुकूल परिवर्तित या ढालने म असफल रहते हैं। अधिकाश यायाधीश वढ़ होते हैं, वे पूर्व निर्धारित सामाजिक एव आधिक धारणाओं में बैंधे होते हैं। उनका परित्याम करना उनके लिए सम्मव नहीं होता है, फलस्वरूप वे सामाजिक आवश्यकता को समभने म असफल रहते हैं और प्रगतिशीलता वे मार्ग से अवरोध बन जात हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के सुधार के प्रयत्न

सर्वोच्च यायालय और कांग्रेस या राष्ट्रपति के मध्य कशमक्श कभी-कभी अवाखनीय स्थिति उत्पान कर देती है। इस प्रकार का एक समय 1895 ई. म. हुआ था। उस समय यायालय ने यह निषय दिया था कि शासन आय कर नहीं लगा सकता है। सर्वोच्च यायालय की इस निणय के कारण तीव्र आलोचना हुई है। ड्रेंड स्काट (Dred Scott) विवाद17 म दियं गये निणयं म सर्वोच्च यायालयं ने नीग्री की स्वत-"त्रता को स्वीकार नहीं किया था। अब्राहम लिंकन ने इस निणय को विवेकहीन, असगत एव राजनीतिक इंप्टिकोण से प्रेरित बताया था। इन सब कारणी से यह अनुसब किया गया था कि यायाधीको की स्वतानता एव लोकमत को समन्वित एव सम्बन्धित करने की किसी न किसी प्रकार की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अपने पू डील कायकम के सादभ में ऐसा ही मत व्यक्त किया था। उनका कथन था कि मदि सर्वाच्च यायालय यायिक पुनरीक्षण के अधिकार के कारण ततीय सदन बना रहा तो देश की प्रगति तथा लोक उल्याणकारी राज्य के विकास के अवरुद्ध हो जाने की सम्मादना है। सर्वोच्च 'यायालय की उपरोक्त उल्लिखित आय कर सम्ब'धी निणय का निष्प्रमावी करने के लिए 16वा सशोधन पारित करना पडा था। सर्वाच्च "यायालय के निणय सदैव वैधानिकता से सम्बाधित नहीं होते। अनेक अवसरी पर सर्वोच्च "यायालय के निणयों में राजनीतिक पूट होता है। इस स्थिति को रोकने के लिए सर्वोच्च यायालय के सगठन एव कायपद्धति सम्बाबी सुधार के बारे में अनेक मुभाव दिये गये हैं, यथा-विधिया को अवधानिक घोषित करने वाले निणय सर्वाच्च यायालय द्वारा वहुमत की अपेक्षा कुल सदस्या के दो तिहाई बहुमत से दिये जान चाहिए । एक अय सुकान के अनुसार सर्वोच्च यायालय द्वारा अवधानिक घोषित की गयी विधिया को काँग्रेस को पुन उसी प्रकार पारित करने का अधिकार होना चाहिए जिस प्रकार कि राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत विधियो को काग्रेस पुन पारित कर सकती है। यायिक पुनरीं साथ की शक्ति को ही समाप्त कर दन के भी सुभाव दिये गय है। यह सभी सुभाव किया वित नहीं हो सके हैं और न इनके किया वित होने की काई आशा ही है क्यांकि अमेरिकी जनता को बहुमत म कोई आस्या नही है । अत वर्न

एव पेस्टासन "यायिक पुनर्रीक्षण सं युक्त स्वत"न न्यायपालिका का विधानमण्डत एव जनता के बहुमत के सम्मावित सुस्तक्षेप के विषद्ध एक सस्यागत व्यवस्था मानते हैं।

1937 ई म अमेरिको राष्ट्रपति रूजवस्ट ने सर्वोच्च यायालय के नुपार के सम्बाध म प्रस्ताव उपस्थित किये थे। 1933 ई म फकलिन डी रूजवेल्ट राष्ट्रपति बने थे। उस समय विश्वव्यापी आर्थिक मादी के सम्मावनाओं से अमेरिकी अय व्यवस्था जजर हो रही थी। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इस स्थिति का सामना करने के लिए एक महत्वाकाक्षी कायक्रम प्रस्तुत किया था। यही पू डील कायक्रम कहलाता है। इस कायक्रम के अत्तरत कांग्रेस ने अनेक विधिया पारित की थी। इस कायक्रम से सम्बंधित विवियो का इनसे प्रमावित विभिन्त हितो द्वारा यायालय मे चुनौता दी गयी तथा सर्वोच्च यायालय ने इनम से बारह विधिया को अवधानिक घोषित किया था । राष्ट्रपति रूजवेल्ट इससे क्षुब्ध हा गये । उन्होंने सर्वाच्च यायासय के विरोध की निष्प्रमानी करने के लिए एक प्रस्ताव उपस्थित किया जिसक अनुसार प्रत्येक ऐस पापाधीश के स्थान पर जा 10 वप तक पद पर काय कर चुका हो तथा 70 वप की आयु पार कर चुका हा, एव अतिरिक्त बायाधीय नियुक्त करने का अधिकार गप्टपति की देने का प्रस्तान था, नशर्ते यायाधीशा की कुल सदस्य सरया 15 से अधिक न हो जाय । इस प्रस्ताव का उद्देश्य सर्वाच्च यायालय म नवीन रक्त का समावेश करना तथा उसे रूटिवादी होने स रोक्ना था। राष्ट्रपति के प्रस्तावा का तीज विरोध किया गया और अत म वे अस्वीकार कर दियं यय । परातु योगस न एक विधि पारित की जिसके अनुसार यायाधीया को 10 वप की संवा के परवात 70 वय की आयु पर सवेतन पदिनवित्त की व्यवस्था थी । यदापि रूजवेस्ट जपन प्रस्ताव की पारित न करा सके पर तु उपरोक्त विधि में उनका उद्देश्य पूण हा गया । यह सत्य है कि सर्वाच्च यायालय न अमेरिकी जनता एव राष्ट्र की प्रशसनीय सेवा की है। यह शासनतात्र का सातुलन चक्र है। उसने सविधान की देश का सर्वोच्च विधि के रूप म रक्षा एव व्याख्या की है। यह विश्व का महानतम न्यायिक सगठन एवं अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली का एक समक्त तत्व है। सास्की के अनुसार अम रिकी संघीय पायालय विशेषकर सर्वोच्च यायालय का जितना सम्मान है उतना ही सयुक्त राज्य अमरिका के जीवन म उसका प्रमाव भी है। यह बहना अतिहासारित-पूण नही होगा कि अमेरिकी इतिहास (सर्वोच्च 'यायासय) द्वारा दिये गये संघीय निणया पर विचार के अभाव म अपूण रहेगा।18

^{18 &#}x27;The respect in which the federal courts and above all, the Supreme Court are held ishardly surpassed by the influence they exert on the life of the United States It is not excessive to say that American history would be incomplete without a careful consideration of them"—Laski The American Democracy, 1953, p. 110

भारतीय न्यायपालिका [THE INDIAN JUDICIARY]

सपुक्त राज्य अमेरिका की माति भारत म के द्र एव राज्या की पृथक एव हुइरी यायपालिका नहीं है। भारतीय यायपालिका एकीकृत (integrated) है जिसके शीप पर मारतीय सर्वोज्य यायालय है और उसके नीचे प्रत्यक राज्य म एक उच्च मायालय तथा राज्या म जिला-स्तर पर जिला यायालय एव उप जिला याया लय होते हैं। मुस्कि की अदालते यायपालिका की छोटी अदालते हैं। इसने अतिरिक्त अप मजिल्ट्रेट भी अपराधिक विवादा का निजय करते है। जिला यायालय के याया औश एव मुस्तिक तथा अ य दण्डाधिकारी (प्रथम एव द्वितीय थेणी) लोक देवा आयोग द्वारा प्रतियोग परीक्षाओं के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किय जाते हैं। जिला यायालय तक मुस्तिक अधिकारिया की पदोन्नति होती रहती हैं। वरिष्ठता एव योग्यता पदोन्नति के मुख्य आधार हैं। साम पदामत यायालय सबसे छोटी अदालत है।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

मारतीय सर्वोच्च यायालय देश की यायपालिका के शीप पर स्थित है तथा यह सर्वोच्च एव एकमान संधीय यायालय है। सविधान द्वारा सर्वोच्च यायालय के न्यायाधीशा की संख्या मुख्य बाबाधी? महित 8 निर्धारित थी और संसद को इस संख्या में बिद्ध का अधिकार दिया गया था। 1960 ई के संधीधन के अनुसार मुख्य ग्यायाधीशा की संख्या 14 निष्कृत की गयी है। अस्थायी ग्यायाधीशा की निर्धुक्त की संबंधी है। अस्थायी ग्यायाधीशा की निर्धुक्त करता समय राष्ट्रपति सर्वोच्च ग्यायाधीशा की निर्धुक्त करता समय राष्ट्रपति सर्वोच्च ग्याया संबच्च अथा उच्च ग्यायाधीश की निर्धुक्त करता समय राष्ट्रपति सर्वोच्च ग्याया स्था अथवा उच्च ग्यायाधीश की हित्रुक्त करता समय राष्ट्रपति सर्वोच्च ग्याया स्था अथवा उच्च ग्यायाधीश के ऐसे वावाधीशो से परामय लेटा है जिनसे वह इस सम्ब ध मे परामश करना उच्चित समनता है तथा मुख्य वावाधीश में वह पर ग्यायाधीशा की निर्धुक्ति करना स्थान द्वारा निर्धारित ग्यायाधीशा की निर्धुक्ति के सन्धम मं परामश करना उच्चित समनता है। सविधान द्वारा निर्धारित ग्यायाधीशा की निर्धुक्ति के सन्धम मं परामश करना स्थान हारा निर्धारित ग्यायाधीशा की निर्धुक्ति के सन्धम मं परामश करना स्थान स्थान हारा निर्धारित ग्यायाधीशा की निर्धुक्ति के सन्धम मं परामश करना स्थान स्थान हारा निर्धारित ग्यायाधीशा की निर्धुक्ति के सन्धम मं परामश करना स्थान स्थान स्थान हारा निर्धारित ग्यायाधीशा की निर्धुक्ति के सन्धम मं परामश्च करना है। स्थानधान द्वारा निर्धारित ग्यायाधीशा की निर्धुक्ति के सन्धम मं परामश्च करना है। स्थानधान द्वारा निर्धारित ग्यायाधीशा की निर्धुक्ति के सन्धम परामश्च करना स्थान स्

धीशा की योग्यताएँ निम्नवत् हैं 1 वह भारत का नामरिक हा, कम स कम 5 व्य तक किसी उच्च यायाजय मे यायाधीश रह चुका हो अथवा किसी उच्च यायालय म कम से कम 10 वप तक अधिवक्ता के रूप में काय कर चुका हा या राष्ट्रपति की हव्दि म विख्यात विधिविज (Emment Jurist) हो । सर्वोच्च यायालय का 'पापा घीरा 65 वप तक पदासीन रहता है। इसके पूर्व उसे स्वय त्यागपत्र देकर पद में पूर्वक हाने का अधिकार है। कदाचार एव असमथता के कारण ससद महामियाग लगाकर "पापाधीशों को पदच्युत कर सकती है। महामियोग के स्वीकृत होने के लिए तत्सम्बधी प्रस्ताय को समद के एक ही सब भे दोनो सदना द्वारा प्रथक प्रथक रूप मे सदनों के कूल सदस्यों की सल्या के स्पष्ट वहमत एवं उपस्थित सदस्या के दो तिहाई बहमत से पारित होना चाहिए। इस प्रकार महामियोग प्रस्ताय के पारित होने पर मारतीय पायाधीश का पद से प्रथक करने का अधिकार राष्ट्रपति का प्राप्त हो जाता है। मुख्य स्यापाधीश को 5 हजार एव अन्य "यायाधीशों को 4 हजार रुपये माहिक वेतर दिया जाता है, विना किराये का सरकारी आवास प्राप्त होता है तथा समचित भने की क्यवस्था होती है एवं अप सुविधाएँ भी प्राप्त हु । न्यायाधीशो के वतन, मले एवं अ य स्विधाओं मे उनके कामकाल में कोई कभी नहीं की जा सकती। अवकाश ग्रहण करने के पदचात सर्वोच्च यायालय का कोई भी यायाधीश विसी भी मारतीय यायालय मे बकालत नहीं कर सकता। उनके वेतनादि भारतीय सचित शिथ पर मार होते हैं। महानियोग की कठित व्यवस्था करने न्यायाधीशों को कायकाल सम्याधी सुरक्षा प्रदान की गयी है। अय व्यवस्थाओं से यायाधीशों को आर्थिक चिताओं से मुक्त होकर स्वतन्त्रता एव निर्मीकतापुरक अपने दायित्व को सम्पादित करने के अवसर प्रदान निर्मे गये है।

सर्वोच्च पायालय का क्षेत्राधिकार एव शवितयाँ

सर्वोच्च यायालय का व्यापक क्षेत्राधिकार एव अनन्य सक्तियाँ प्राप्त हैं

1 भौतिक या प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction)

उस निम्न प्रकार के विवादा म मौतिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है

(1) मारत सरकार तथा एक या एक स अधिक राज्या के मध्य विवाद,

(n) राज्य या राज्या तथा एक या अधिव राज्या के मध्य विवाद

(m) राज्या के मध्य सवधानिक विषया सम्बन्धी विवाद, एव

(IV) सविधान के त्रिया वयन के पूत्र सम्पादित सचि या सनद की व्ययस्या स सम्बन्धित विवाद।

उपराक्त वित्रादा म नेवल सर्वाच्च "यायालय का ही मीलिक क्षत्राधिकार प्राप्त

¹ The Union Judiciary, Ch IV Articles 124, 126 and 127

² अनुस्टेर 131

है, पर तु मोतिक अधिकारो सम्ब धी विवादा मे सर्वोच्च यायालय के साथ साथ उच्च यायालयों को भी मोतिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यदि वादी चाहे तो मौतिक अधि कारों सम्ब धी विवाद को सवश्रथम उच्च यायालय म या सर्वोच्च यायालय में भी प्रस्तुत कर सकता है। अत मोतिक अधिकारों के सम्ब ध में सर्वोच्च यायालय को राज्यों के उच्च यायालयों के साथ समवर्ती क्षेत्राधिकार प्राप्त है। मौतिक अधि-कारों के रक्षाय यायालय विभिन्न प्रकार के लेख (Writs) अर्थात व दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिशेष (Prohibition), अधि-कार पृच्छा (Quo warranto) एव उत्प्रवण (Certiorari) जारी करने का अधिकार प्राप्त है।

2 पुनरावेदनीय (अपीलीय) क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction)

भारतीय सर्वाच्च यायालय देश का अितम पुनराबेदनीय यायालय है । कि सारतीय सर्वाच्च यायालय देश का अितम पुनराबेदनीय यायालय है । कि सारतीय के उच्च यायालया के निजयों के विच्छ दीवानी एव फौजवारी विवादों में अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। स्वत नता के पूव उच्च यायालया के निजयों के विच्छ अपीलें प्रीवी परिषद द्वारा सुनी जाती थी। पर तु 1949 ई मे प्रीवी परिष्य के क्षेत्राधिकार के उम्मुलन के फलस्वरूप वहा अपीले जाना व व हो गया है तथा विवादा द्वारा सर्वोच्च यायालय को सभी विवादों में अन्तिम अपीलीय क्षेत्राधिकार प्रवान किये गये हैं। सर्वोच्च यायालय स्वय अपने आदेशों एव निजयों पर पुनर्विचार कर सकता है पर तु उसके निजय के विच्छ अपील नहीं की जा सकती है। इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के विच्या वाता है वीवानी, अपराजिक (फौजवारी), यद्यानीक एव विविष्ट ।

- (1) दीवानी—केवल उही दीवानी विवादों की अपील की जा सकती है जिनका सम्बन्ध 20 हुजार रुपये की धनराशि या जायदाद से हो तथा सर्वाच्च "याया लय द्वारा तत्सम्बन्धी प्रमाण-पन प्रदान किया ब्या हो। लेकिन उच्च "यायालय के किसी ऐसे निणय के विरुद्ध सर्वोच्च "यायालय से अपील नहीं की जा सकती जा केवल एक यायाधीश द्वारा दिया गया है।
- (1) अपराधिक—उच्च यायालयो ने निम्न अपराधिक विवादा के निणया के निरुद्ध सर्वाच्च यायालय मे अपील सम्मव है—(अ) ऐसा विवाद जिसने उच्च याया-लय द्वारा नीचे की अदालत के ऐसे निणय को जिसम अपराधी को अपराध से मुक्त किया गया हो, रह करके अनियुक्त को मृत्युरण्ड दिया हो, (य) किसी अपीन एव निम्न यायालय में चल रह विवाद को अपने यहीं मैगाकर उच्च यायालय में मरपु-रण्ड दिया हो, या (स) उच्च यायालय ने विवाद को सर्वोच्च यायालय में मरपु-

³ अनुच्छेद 137

ये योग्य प्रमाणित किया हा । समद ना सर्वाच्च वावालय के क्षेत्राधिकार को विस्तृत करने भी शक्ति प्राप्त है ।

(m) सबधानिक-सर्वाच्च पायालय में ऐसे सभी दीवारी, अपराधिक या जय विवादा के उच्च यायालया के निषया के विरुद्ध अपीले हो सकती हैं जिनके सम्य ध म उच्च यायालय न यह प्रमाणित किया हो कि सम्बन्धित विवाद में विधि एव सविधान की व्यान्या सम्बाधी कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है। धादि उच्च याया लय द्वारा ऐसा प्रमाण-पत्र दना अस्वीकार कर दिया गया है और सर्वोच्च यायालय यह अनुमव करता है कि सम्बर्धियत विवाद म सविधान सम्बन्धी विधि का कोई प्रश्न निहित है तो वह अपील की विदोष अनुमति प्रदान कर मक्ता है। जब उच्च 'याया-सम के निणम के विरुद्ध सर्वोच्च "यायासय विशेष अपील की अनुमति प्रदान कर देता है ता सम्बन्धित पक्ष इस आधार पर अपील नर सनता है कि उन्न यायालय हारा सुविधान सम्बाधी विधि की गलत व्याख्या की गयी है । नवीन आधारी पर भी सर्वोच्च "पायालय विशेष अनुमति देने का पक्षपोपण कर सकता है। स्पष्ट है, सबि धान की ज्याच्या का अतिम अधिकार सर्वाच्च यायालय को है। स्मरणीय है कि तस्या एवं किसी ऐसी विधि की व्यास्या (जो सर्विधान की व्याख्या से मम्बर्धित नहीं है) के सम्बाध म विशेष अपील की अनुमति के आधार पर सर्वोक्च यायालय म अपील नहीं की जा सकती है। किसी सवधानिक प्रश्न सम्बाधी विवाद की सुनवाई 5 यायाधीशो की पीठ के द्वारा की जावी है।

(11) विकारह—सर्वाच्च यायालय को यह अधिकार भी है कि वह सिनक "प्रायालयो (Courts Martial) के अतिरिक्त बारत के किसी भी यायालय या पाण धिकरण के विकट अभील की वि पेणकुमित प्रदान कर सकता है एवं अपील की सुन सकता है।

उपरोक्त अपीलीय क्षेत्राधिकार के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च याया-लय म अपील के तीन माग हैं (1) उच्च यायालय के प्रमाण पत्र द्वारा, (2) सर्वोच्च प्रापालय की विगेषानुमति द्वारा (special leave to appeal) एवं (3) स्वाधिकार द्वारा (as a matter of right) !

सर्वोच्च 'मायालय के द्वारा व्यपित की विशेषानुवित-सर्वाच्च यायानय हो भारत के किसी भी 'ग्रायालय वा 'यायाधिकरण के विरुद्ध अपील की अनुमति देन का स्वविवेकीम अधिकार प्राप्त है, फलस्वरूप सर्वोच्च 'यायालय का व्यापक अधिकार प्राप्त हो गये हैं। इस अधिकार का अय यह है कि पुनरावेदनीय व्यवस्था हे अधीन

⁴ अनुच्छेद 132 (1)

⁵ अनुच्छेद 132 (u)

⁶ अनुच्छेद 136

अभील न कर सकने पर⁷ एव उच्च यायालय द्वारा पुनरावंदन के लिए प्रमाण पत्र अस्वीकृत करने पर भी सर्वोच्च यायालय को अपील की अनुमति देन का अधिकार प्राप्त है। यायालय द्वारा विशेषानुमति प्रदान करने पर कोई सर्वैधानिक प्रतिव धन्ति हैं। सर्वोच्च यायालय के स्वविवेक पर आवारित हैं। सर्वोच्च यायालय के स्वविवेक पर आवारित हैं। सर्वोच्च यायालय ने सारत बैक कमचारी विवाद के सदम में इस पर विचार किया था कि जुनरावेदन की विशेषानुमति के अन्तमत औद्योगिक यायाधिकरण में आते हैं या नहीं? इस सम्ब पे में सर्वोच्च यायालय का यह सर्व था कि यायाधिकरण से तालय स्वयिक काम सम्बादित करने वाले निकाय से हैं। सर्वोच्च यायालय का स्व सर्व था कि यायाधिकरण से तालय स्वयिक काम सम्बादित करने वाले निकाय से हैं। सर्वोच्च यायालय ने रामकृष्ण बोस बनाम विनोद को नुमन्तो नामक विवाद म राज्य विधानमण्डल के इस निषय को अस्वीकार कर विया था कि जल प्रतिनिधित्व अधिनियम जैसे अधिनियमों के अन्तगत गठित यायाधिकरण के निषय अतिम होगे। सर्वाच्च यायालय के मतानुसार अनुच्छेद 136 के अन्तगत उसे प्राप्त के भागत को प्राप्त के भागत के भागत से के प्राप्त के भागत से भा

विषेपानुमति सम्बाधी अनुच्छेद का क्षेत्र व्यापक है और इसकी कोई निश्चित मीमा निर्धारित नहीं को आ सकती। इसका प्रयाग विचारपूवक किया जाना अपे-क्षित है अत सर्वोच्च यायालय अपील की विषेपानुमति विशिष्ट परिस्थितियो तथा गम्भोर आयाय की अवस्था में ही प्रदान करता है।

3 परामशवायी क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction)

राष्ट्रपति को सावजनिक महत्व से सम्बधित किसी तथ्य या विधि सम्ब धी प्रश्नों को यह सर्वोच्च पायालय का परामक्ष प्राप्त करने का अधिकार है एवं ऐसे प्रश्नों को यह सर्वोच्च पायालय का परामक्ष प्राप्त करने का अधिकार है एवं ऐसे प्रश्नों को यह सर्वोच्च पायालय का मत जानने के लिए भेच सकता है। व सायालय के राज्या में हुई किसी में सिंध, सनद एवं अप सासकीय पत्र (document) सम्ब धी विवाद पर राज्यूपति सर्वोच्च पायालय से परामक्ष ने सकता है। याधालय के द्वारा प्रवत्त परामक्ष राष्ट्रपति पर व धनकारी नहीं है। अभी तक राष्ट्रपति द्वारा निम्म अवसरा पर सर्वोच्च पायालय से परामक्ष माया गया है (1) 1951 ई म दिल्ली विधि अधि नियम (1912), अवमेर मारवाड (एक्सटेशन ऑफ लॉच) अधिनियम (1947) तथा माय 'ख' राज्य अधिनियम (1950) की वैधता के सम्ब ध म मत, (2) केरल विशो विधेयक 1957 ई की वचता सन्व पी मत, (3) 1958 ई मारत एवं पाय प्रपान सिममीत के सच्च वेस्वारी शेन का वाकिस्तान के हिस्ता वरित करने सम्ब धी सममीत सम्ब धी मत । प्रकृत यह धा कि नया हस समक्रीत के किया वयन के लिए सबैधानिक

⁷ अनुच्छेद 132-135

⁸ अनुच्छेद 143

र माध्य प्रमाणित स्थित हा । समर का मर्थान । वायालय न क्षत्राधिकार की किन्तु कर । की शक्ति प्राप्त है ।

(m) संबंधानिक-संबंध्य वाबासय म एस मुना दीवानी, अवराधिक मा अप विवादा में उपन वापालया न निषया न विवद्ध अपीलें हो सरती है जिनक सम्ब भ म उच्च वायासय र यह प्रमाणित क्या हा कि सम्बर्धित विवाद म विधि एव सविधात नी स्थान्या मध्याधी बाई महत्वपुत्र प्रस्त निहित है । यदि उपन पाया सम द्वारा एसा प्रमाण अत्र दशा अस्त्रीकार कर दिया गया है और सर्वोच्च "यापालय मह अनुमव बारता है जि सम्बाधित विवाद म सविधान सम्बाधी विधि का कोई प्रश्त निहित है ता यह अपील की विशेष अनुमति प्रदान कर सकता है। अब उच्च "याया-सम य निषय में विषय सर्वाच्य मायासय विशेष अपील की अनुमति प्रदान कर दता है हा सम्बर्धित यहा इस आधार पर अपील बर सकता है कि उच्च यामालय द्वारा सविधान सम्बन्धी विधि की बलत व्यान्या की नवी है । नवीन आधारा पर भी मर्जाच्य 'वामालय विद्येष अनुमति दन का पक्षपीयण कर सकता है । स्पट्ट है, सर्वि-धात की अग्राम्या का अस्तिम अधिकार सर्वाक्त यायालय को है। स्मरणीय है कि तथ्या एवं निसी ऐसी विधि की ब्याख्या (जो सर्विधान की ब्याख्या स सम्बद्धित नहां है) क सम्बाध म विशेष अपील की अपुनति के आधार पर सर्वोच्च यायासय म अपील नहीं की जा सकता है। किसी मबधानिक प्रस्त सम्बंधी विवाद की स्तवाई 5 यायाधीशा की बीठ के द्वारा की जाती है।

(IV) विशिष्ट—सर्वाञ्च प्रायालय को यह अधिकार भी है कि वह सर्गिक प्राप्तालया (Courts Martial) के अतिरिक्त भारत के किसी भी प्रायालय या न्याया पिकरण के विश्वद्ध अपील की विशेषानुमति प्रदान कर सकता है एवं ज्योग को सुन

सकता है।

जपरानत अपीतीय क्षेत्राधिकार के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि मर्वोच्च याया-लय में अपील के तीन मांग हैं (1) ज्व्च यायालय के प्रमाण पत्र द्वारा (2) सर्वोच्च यायालय की निजेषानुमति द्वारा (special leave to appeal) एवं (3) स्वाधिकार द्वारा (as a matter of right)।

सर्वोच्च पायालप के द्वारा अपील की विशेषानुमृति सर्वाच्च पायालप की भारत के किसी भी पायालप या यायाधिकरण के विरुद्ध अपील की अपुपति देने का स्वविवकीय अधिकार प्राप्त है, फनस्वरूप सर्वोच्च पायालय को ज्यापक अधिकार प्राप्त हो गये हैं। इस अधिकार का जब यह है कि पुनरावेदनीय ब्यवस्था के अधीन

⁴ अनुच्छेद 132 (1)

⁵ अनुच्छेद 132 (II)

⁶ अनुच्छेद 136

अपील न कर सकने पर प्र अञ्च यायालय क्षारा पुनरावेदन के लिए प्रमाण पत्र अस्वीकृत करने पर भी सर्वोच्च यायालय को अपील की अनुमति देन का अधिकार प्राप्त है। यायालय द्वारा विश्वपानुमति प्रदान करने पर कोई सर्वधानिक प्रतिव धनहीं है और यह पूर्णत सर्वोच्च यायालय के स्वविवेक पर आधारित है। सर्वोच्च यायालय के प्राप्त ने भारत वैक कमचारी विवाद के सर्वभं में इस पर विचार किया था कि पुनरावेदन की विशेषानुमति के अरुवात लीखोगिक यायाधिकरण भी अते हैं या नहीं? इस सम्ब ध में सर्वोच्च यायालय का यह भत था कि यायाधिकरण से ताल्प यायिक काम सम्पादित करने वाले निकाय के हैं। सर्वाच्च यायालय ने रामकृष्ण बोस बनाम विनोद करने वाले निकाय से हैं। सर्वाच्च यायालय ने रामकृष्ण बोस बनाम विनोद कामृत्तमों नामक विवाद म राज्य विधानमण्डल के इस निणय को अस्वीकार कर दिया था कि जन प्रतिविधिद्य अधिनियम जसे अधिनियमा के अन्त्रान गठित यायाधिकरण के निणय की तम होगे। सर्वोच्च यायालय के प्रतानुवार अनुच्छेद 136 के अन्यनत हो प्राप्त के भागत हो किया जा सकता।

विद्योपानुमति सम्ब बी अनुच्छेद का क्षेत्र व्यापक है और इमकी कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। इसका प्रयोग विचारपुषक किया जाना अपे-क्षित है अन सर्वोच्च यायाजय अपील की विशेषानुमति विशिष्ट परिस्थितिया तथा गम्भीर अयाय की अवस्था म ही प्रदान करता है।

3 परामशत्रायी क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction)

राष्ट्रपति का सावजिनक महत्व से सम्बी वत किसी तथ्य या विधि सम्बाधी प्रश्न पर सर्वोच्च यायालय का परामक्ष प्राप्त करने का अधिकार है एव ऐसे प्रश्ना को वह सर्वोच्च यायालय का परामक्ष प्राप्त करने का अधिकार है एव ऐसे प्रश्ना को वह किसी मी सिक, सनद एव अय शासकीय पत्र (document) सम्बाधी विवाद पर राष्ट्रपति मर्वोच्च मागालय से वरामख ने सकता है। यायालय के द्वारा प्रदत्त परा मग्र राष्ट्रपति पर व वनकारी नहीं है। अभी तक दाष्ट्रपति द्वारा तिनम अदस्य परा मग्र राष्ट्रपति पर व वनकारी नहीं है। अभी तक दाष्ट्रपति द्वारा तिनम अदस्य परा मग्र राष्ट्रपति पर व वनकारी नहीं है। अभी तक दाष्ट्रपति द्वारा तिनम अदस्य पर सर्वोच्च यायालय से परामग्र माँगा गया है (1) 1951 ई म दिल्ली विधि अधि नियम (1912), अजभीर भारवाड (एनसटेदान ऑफ लॉज) अधिनियम (1947) तथा माग्र 'ख' राज्य अधिनियम (1950) की वचता के सम्ब प म मत्र (2) केरल विशा विधेयक 1957 ई की वैधता सम्बधी मत्र (3) 1958 ई म मारत एव पाच माम्नीत विधेयक पाच से सम्बधी सेन सम्बधी के किया नयन के लिए सवधानिक सम्बधी मत्र। प्रश्न यह या कि क्या इस समभीते के किया नयन के लिए सवधानिक

⁷ अनुच्छेद 132-135

अनुच्छेद 143

सत्तापन आवस्यक है ? (4) 1964 ई. म उत्तर प्रदश्त म व्यवस्थापिका एवं उत्त

सर्वोच्य "सावालय प्राप्त परामशदायी विवादा म सुती अदालत म बहुमत क चायातय है मध्य उत्पन्न विवाद के सदम म। आधार पर निषय दिव जात हैं। यदि कोई यागाधीन बहुमत व निषय से असहमत रहता है तो वह अपना पूपक निणव द सकता है। एत विवादा की सुनवाई सर्वोच्च

न्यामालय के पांच यामाधीता की पीठ (Bench) द्वारा की जाती है। सर्वोचा चायालय ना परामद्भदायी क्षेत्राधिनार प्रदान करना तीव विवाद था विषय रहा है। सविधान मिसाताना ने सभी तकों की समीक्षा करने के पश्चात ही इसके पक्ष म निणय लिया था। महत्य की बात यह है कि सर्वोज्य यायालय क परामश्रदायी निषम राष्ट्रपति पर व पनकारी नहीं है पर तु यायालय हारा जो सी न्यान्यन्त्रम् अन्य प्रमुख्यः समुद्धितं सायता प्रदानं की संयी है। देश क सभी यापालवा के लिए हा निणया का विशेष महत्व होता है।

नारतीय सर्वोच्च वायालय एक अभिनेख यायालय है एव ऐसे वायालय को 4 अभिनेख चायालय (Court of Record) सारताय चयाण्य प्राप्ताय प्राप्ताय है । अभिलेख यायालय के वो आशाय माप्ता सभी शक्तियों इस यायालय को भी प्राप्ता हैं। अभिलेख यायालय के वो आशाय नारा प्राप्त कर कार्य है सभी निषय एवं काप समस्त यायालयों के लिए होते हैं (1) अभिनेल यायालय के सभी निषय एवं काप समस्त यायालयों के लिए हात द (१) जानाचा जाता के प्रवास किये जाते हैं एवं अभितेखों (records) की सत्यता एवं सर्वा साक्षी के रूप म स्वीकार किये जाते हैं एवं अभितेखों (स्तवा सावा। क व्यव व रवाकार १ कव वास २ र व वास वा सकता। अपिन प्रमाणिकता के सम्बाध में किसी बायालय में कोई प्रदर्ग नहीं उठाया जा सकता। अपिन प्रमाणकथा क सम्बन्ध अभितेली एवं पत्रो म साधारण भूती एवं गुटिमा के सघी लल थापालय का लगन लागराच्या प्रेम न्या प्रस्ता प्रमु तुष्टाया का तथा धन का स्वय अधिकार होता है। (2) बाबालय के अपमान के लिए अभिनल यावा था का रचन आनकार वार्ण व र र न । सम दण्ड दे सकता है। सर्वोच्च सामालय के निषय नजीरा का काय करते हैं तथा प्तम पुरक्षित रहे जिससे आबस्यकतानुसार उनका अध्ययन क्यि जा सके।

याधालय क धाराव्यक्त स्वांक्त सर्वोच्च यायालय के क्षत्राधिकारों को सविधान ने ससर्व को विधि बनाकर सर्वोच्च यायालय सर्वोच्च यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार सावधान न सार्थ । अधिक अधिकारों की रक्षा के जिए सर्वोच्च विस्तृत करन का अधिकार दिया है। सीविक अधिकारों की रक्षा के जिए सर्वोच्च विस्तत करन का जानकार ज्या है (writs) खारी करने का अधिकार है। 10 प्राचालय को आदेश, निर्देश या सेख यायात्तव का लावक, गण्यज वर जन्म हुन हुन करने के लिए ससद को सर्वोच्च पाया सिवधान द्वारा प्रदत्त ≣ियलों को सम्यादित करने के लिए ससद को सर्वोच्च पाया सावधान क्षाच नवर = वान्त्रवा प्रदान करने का भी अधिकार प्राप्त है लेकिन ऐसी लग को अस अतिरिक्त अस्त्रियों प्रदान करने का भी अधिकार प्राप्त है लेकिन ऐसी लय का अब आधारण थाएला वचार करें ज्या के विषयीत नहीं होना चाहिए ।11 सर्वोडब किसी विधि को सर्विधान की किसी घारा के विषयीत नहीं होना चाहिए ।11 सर्वोडब ाक्षा ।वाव का चार्यभाग का स्थाप को अपने समक्ष प्रस्तुत करने की आणा दे सबता न्यापालय किसी व्यक्ति या कागजात की अपने समक्ष प्रस्तुत करने की आणा दे सबता

⁹ अनुन्छेद 138

¹⁰ अनुच्छेद 139

[।] अनुन्छेद 140

है। राष्ट्रपति एव शासन के अप अधिकारियों का यह क्तव्य है कि वे सर्वोच्च पाया तय के आदेशा एव निर्देशों को क्रियानित करें।

सर्वोच्च न्यायालय एव मौलिक अधिकार"

मौलिक अधिकारो की रक्षा का दायित्व सर्वोच्च यायालय पर है। 13 उसे अधिकारों की रक्षा के लिए आदश, निर्देश एव लेख (writs) जारी करने का अधिकार है। लेख जारी करने का अधिकार उच्च यायालया को भी प्राप्त है,14 लेकिन अनुच्छेद 32 (1) वे अत्तगत मौलिक अधिकारो की रक्षा सर्वोच्च पायालय का विशेष दायित्व है। रमेश थापर बनाम मदास राज्य नामक विवाद मे निणय देते हुए सर्वोच्च यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि "मौलिक अधिकारो के रक्षाय प्रत्येक नागरिक को उच्च यायालय की अपेक्षा सीधे सर्वोच्च यायालय म आवेदन करने का अधिकार है। इस हृष्टि में सर्वोच्च यायालय मौलिक अधिकारों का सरक्षक है, अत वह मौलिक अधिकार का अतिनमण होने की दशा म उसके सरक्षण से इ कार नहीं कर सकता।" एक अय विवाद (रामजीलाल बनाम इनकम टक्स अधिकारी) म सर्वोच्च यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि अनुच्छेद 32 के अतगत मौलिक अधिकार क अतिक्रमण की अवस्था म ही आवश्यक सरक्षण प्राप्त हो सकता है, अप्य किसी सबैधानिक अधिकार के सरक्षण के लिए इस अनुच्छेद (अनु 32) का उपयोग सम्मव नहीं है। इसके अतिरिक्त खरनजीत लाल बनाम भारतीय सघ नामक विवाद मे सर्वाच्च यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि अनुच्छेद 32 के अ तगत प्रस्तुत किय जाने वाले आवेदन पत्र मे यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाना चाहिए कि किस विधि द्वारा मौलिक अनिकार का अतिक्रमण होता है तथा उस विधि द्वारा आवेदक के मौलिक अधिकार का निश्चित रूप स अतिकमण हुआ है।

मौलिक अधिकारों के सन्दन्न में सर्वोच्च यायालय का दृष्टिकोण एव भूमिका प्रश्नातीय है। समानता के अधिकार सम्ब धी सबसे अधिक विवाद यायालय के समझ आये हैं। समानता के अधिकार सम्ब धी सबसे अधिक विवाद ये सर्वोच्च यायालय के न यह निष्य दिया था कि राज्य शासन को जाति या धम के आधार पर राज्य की शासकोय शिक्षण सस्याओं में प्रवेश हेतु स्थान सुरक्षित करने का अधिकार नहीं हैं। कर-अधिनयमा की कायपद्वित के सन्दन्न में विधि के समझ समानता की प्रतिभू सर्वोच्च यायालय द्वारा प्रदान की गयी है। शोक्षापुर स्थितिम एव बीविंग मिल कम्पनी में कुप्रवाध के सिए शासकीय नियान के सर्वोच्च यायालय ने उचित ठह

¹² इस सदम म मौलिक अधिकारो सम्बाधी अध्याय 33 को भी दिलए।

¹³ अनुच्छेद 32 (2)

¹⁴ अनुच्छेद 226

¹⁵ S R Sharma The Supreme Court in the Indian Constitution, p 124

राया था। सम्बध्धित कम्पनों के एक भागीदार का यह दावा था कि भेन के अप कारखालों पर नियम्भा स्वाधित न करके दासन ने उसके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया है, लेकिन सर्वोच्च याग्रासय ने बाद में मम्बधित विधि को पुन चुनीती दिये जान पर इम आधार पर अवीमानिक घोषात निव्या था कि मालिकों में सित्र्र्सित देने की कोई व्यवस्था नहीं थी। फतत 1955 ई ये चतुब सवधानिक साधिन अधिनियम इम कठिनाई के निवारलाथ पारित करना पदा था।

अर्मिक एव सारकृतिक अधिकारा सम्बन्धी अनेक विवाद मामानय के समक्ष बाते हैं। ऐसे ही एक विवाद महास हिंदू रिलीजियस एव चेरोटेबिल एण्डाउमेट अधिनियम 1951 ई की घारा 21 को तथा उद्योश राज्य के एक समान अधिनियम (1939 ई) की बान 38, 39 एव 46 की एक उप घारा की सर्वाच्य यायास्य हारा अवैधानिक ठहराया गया था।

सम्पत्ति सम्ब पी अविषारा वे सम्ब घ स सर्वाच्च न्यायालय के निणयों ने सबैधानिक सक्षोधन अनिवाय बना विवे हैं। कामेरेकर सिंह बनाम बिहार राज्य विवाद के निणय म बिहार कामीवारी व मूलन अधिनियमी को अवधानिक वोधित विवाद के निणय म बिहार का अमीवारी व मूलन अधिनियमी को अवधानिक वोधित किया गया था। फलस्बच्य 1951 ई ने अवम सबसानिक सक्षोधन पारिव किया गया। कुल मिलाकर इसका परिणाम यह हुआ कि जमीवरी व मूलन सम्ब भी क्षतिपूर्ति की समस्य विधियों न्यायालया ने क्षेत्राधिनार से नुक्त कर वी वयी।

साल 1967 ई य मुख्य यायाधीश श्रो के सुख्याराव न वोसकताब बनाम पत्राव राज्य विवाद म निवाद देते हुए कहा या कि सविधान द्वारा प्रदत्त मीलिक अधिकारा म ससद नो सतीधम या परिवतन नरन नो सतिक नहीं है। यह निवाद विवाद का विवाद न गया। स्मरणीय है कि मीतिक अधिकारों के सरक्षण के सम्बन्ध म स्वॉच्च याया- लय द्वारा सदव ही यह विचार किया गया कि किसी विधि के द्वारा जो प्रतिवध्य स्थापित किया जा रहा है, वह उचित (reasonable) है या नहीं। गोलकनाय विवाद के निवाद ने सामिक अधिकारा म सवीधन द्वारा परिवतन करने से विचत कर दिया। पत्रस्वक्ष यह सवधानिक प्रदन उठ खड़ा हुआ कि वया ससद को मसीधन सम्याधी सम्प्रमु अधिकार नहीं है ? इस वितर्ध के समाधान हेनु द्वारत को 24वर्ष एव 25वर्ष सर्वधानन सवीधन न सरित कर न के 1

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय एव न्यायिक पुनरीक्षण

भारतीय सर्वोच्च यावालय नो सविधान की व्यास्त्या ना अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च यायालय की स्वापना संधीय सविधान के माय सिद्धा तो के अनुकूल है। जिन देशों में शासन की शक्तियों का विभाजन किया जाता है वहाँ मामा यत सविधान की व्याख्या का अधिकार एक निष्पक्ष निकाय-सर्वोच्च यायायल-मी ही दिया जाता

¹⁶ देखिए अध्याय 33- मौलिन अधिनार 1

है। अत सर्वोच्च यायालय सविधान का सरक्षक माना जाता है। यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सर्वाच्च यायालय को विधानमण्डल द्वारा पारित विधियो एवं कायपालिका के कार्यों को सविधान विरोधी होने की दक्षा म असवैधानिक पायित करने का अधि-कार प्रदान करती है।

मारतीय सविधान म कोई एसा अनुच्छेद नहीं जो सविधान को देश की सर्वोच्च विधि घोषित करता हो । सर्विधान निर्माता इस प्रकार की व्यवस्था को अना वश्यक सम अते थे क्यांकि केंद्र एवं राज्यों की सरकारों का स्पष्ट उल्लेख सर्विधान में किया गया है। इनक निर्माण एव शक्तिया का आधार सविधान है। इसके अतिरिक्त सविधान म सवधानिक सशोधन विधि का स्पष्ट उल्लेख है। अत उपरोक्त व्यवस्थाओ के अनुसार सविधान सम्प्रमु है। इसके अतिरिक्त सविधान द्वारा यायालया को विधि का अवैधानिक घोषित करने का अधिकार भी प्रदान नहीं किया गया है। लेकिन किसी स्पष्ट अधिकार के अभाव में यायालय को पुनरीक्षण की शक्ति से बचित नहीं किया जा सका। मारतीय सविधान लिखित एवं संघीय है तथा उसम के द्वीय एवं राज्यो के शासना की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। मौलिक अधिकारी का सविधान म उल्लेख है। यह चारी व्यवस्थाएँ मारतीय सर्वोच्च यायालय को सविधान की व्याप्या का अधिकारी एव सविधान तथा मौलिक अधिकारा का सरक्षक बना देती हैं। शक्ति विमाजन से सविधान ने विभिन्न शासनी पर सर्वधानिक सीमाए निर्धारित कर दी है। इन सीमाआ के अतित्रमण का जय उन समस्त विधियो को यायालय द्वारा अववानिक घोषित करना है जो सविधान विरोधी हा। व्यामाधीश मुकर्जी ने मारतीय सर्वोच्च "यायालय की "यायिक वनरीक्षण की शक्ति के सादम में कहा है कि "मारतका सविधान लिखित है यद्यपि इसमे ब्रिटिश ससदीय प्रणाली के जनेक सिंडा तो को अपनाया गया है, पर त विधि-निर्माण के सादस में संसदीय सम्प्रभुता के सिद्धात को मायता नहीं दी गयी है। इस सम्ब ध में इसने अमेरिकी सिवधान एव उस पर आधारित अय सविधानो का अनुगमन किया है। राजनीतिक सस्थाओ के प्रतिनिधिमूलक होने पर भी अमेरिकी लोग सविधान द्वारा शासन, विधानमण्डल एवं कायपालिका पर निर्वारित प्रतिव धो को सार्वजनिक एवं वैयक्तिक अधिकारी की रक्षा के लिए आवश्यक मानते हैं। ये (प्रतिब घ) बहुमत की निर्कुशता पर अवरोध " मुख्य पायाधीश कीनिया ने गोपालन बनाम मद्रास राज्य विवाद म निणय दते हुए कहा था कि 'यदि मौलिक अधिकारा का किसी विधायी अधिनियम (legislative enactment) द्वारा अतिक्रमण होता है ती यायालया को उस अधिनियम को अतिकमण की सीमा तब अवध घोषित करने का अधिकार है। भारतीय विधानमण्डला पर सर्विधान द्वारा विधायी क्षमता एव मौलिक अधिकार सम्बाधी सीमाएँ निर्धारित की गयी है।

विधायी क्षमता (legislative competence) के अधीन संघीय एव राज्य

सूची के विषयों पर कमरा केन्द्रीय एवं राज्य शासना का विधि निर्माण का अपिकार प्राप्त है। मारतीय संसद को सविधान द्वारा निर्धारित सीमा के अनगत समूण दर्श के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है। यदि केन्द्र या राज्य के द्वारा अन्य सूची ॥ सम्बधित विषयों के मामला म विधि बनायों जाती है तो पायालय का यह कंट्य है कि वह ऐसी विधि को अवैधानिक घोषित करें। समर्वती मुंबे विषयों के सदस में के द्वीय विधि को राज्य की विधि को अपेक्षा प्राथमिकता प्राप्त है एवं राज्य की विधि उस सीमा तक वह के द्वीय विधि को राज्य की विधि की सुचे सुचे होंगे। तक वह के द्वीय विधि को विधि की श्रेष्ट श्री सीमा तक वह के द्वीय विधि को विधि की श्रेष्ट श्री सीमा तक वह के द्वीय विधि को विधि की

मीलिक अधिकारों के कारण जारतीय मसद एवं राज्यों के विधानमण्डमा की हास्तियों सीमित हो पयी है। सविधान के अनुसार विधि के द्वारा मौसिक अधिकारों का असिकमण होने पर सम्बर्ध धत विधि अवेध होगी (अनुच्छेद 13)। इस उपव ध के अमान म भी मौसिक अधिकारों के सरकाण का नाधित्व अपनेंच्य होगों के जारण उसे मौसिक अधिकारों का सितक्षण करते नाली विधियों हो अर्थ धानिक पोधित करने का अधिकार प्राप्त है। मौसिक अधिकार निरपेश नहीं हैं, मिंद धान द्वारा उन पर जो अनेक प्रतिव च सनाये गये हैं वे उचित (reasonable) है या नहीं, यह निषय करना प्राथासय का काय है। सर्वाच्य नायास्य का स्वाच है कि सह देखें कि सविधान प्रदत्त अधिकार पोसिक है न कि प्रतिवन्ध । अत सर्वोच्य नायास्य का प्रतिवन्ध । अत सर्वोच्य नायास्य का प्रतिवन्ध । अत सर्वोच्य नायास्य का प्रतिवन्ध । (Inmissions) नी वधता एवं वीचित्य के परीक्षण का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

भारत ये सविधान की सर्वोच्चता है न कि ग्रेट विटेन की माति ससदीय सर्वोच्चता। भारतीय सनव एव राज्यों के विधानमण्डलां की अपन अपने क्षेत्रों मं विधि निर्माण का अधिनार है। ऐसी स्थिति म स्पटत आरतीय सर्वोच्च प्याचान को स्वति को स्वति है। इसके अतिरिक्त सर्वाच्च प्याचान के स्वति की स्वति की स्वति की स्वति की स्वति की स्वति की स्वत्य तो जाती है। ऐसी सप्य मारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं तो बातों अत सविधान की रक्षा प्राप्ताधीयों का दाविष्य है। संविधान निर्माताओं ने व्यति व्याच्यत्य के तिष्ट 'सिंव पान के सरक्षक', 'लोकत प्रके रक्षक' एव 'स्वत्य नताओं ना समयक' आदि सम्बोधना का प्रयोग किया था। स्पट है कि सविधान निर्माता सर्वोच्च प्याप्तावय से व्यक्ति एवं समाज की विधिया एव क्यापातिका के कार्यों से अति प्रमाण की रक्षा प्रयोग पिक्या था। स्पट है कि सविधान निर्माता सर्वोच्च प्राप्तावय से व्यक्ति एवं समाज की विधिया एव क्यापातिका के कार्यों से अतिप्रमण की रक्षा की श्रेक्षा करते है। अत मारतीय प्यापातिका (सर्वोच्च प्यापात्य एव उच्च प्राप्तावया) को प्राप्ति पुनराचनोचन की स्वित है और उसके प्रयोग के मध्य'य म नोई विद्यत नहीं उठता।

भारत मे 'याधिक पुनरावलोकन का क्षेत्र

मारतीय सर्वोच्च 'यायालय को अमेरिकी सर्वोच्च 'यायालय की मौति व्यापक

पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त नहीं है। अमेरिकी सर्वाच्च यायालय द्वारा किसी विधि की सर्वधानिकता एव असवधानिकता सम्ब वी परीक्षण के लिए दो कसोटियो का प्रयोग किया जाता है (1) क्या विवि उसका निर्माण करने वाले विधानमण्डल के क्षेत्रा-विकार मे है, अर्थात विधायी क्षमता के आधार पर। (2) क्या विधि 'विधि की उचित प्रक्रिया' (due process of law) की शर्तों के अनुरूप है ? सयुक्त राज्य अमे-रिका में विधायी क्षमता का आधार शक्तियों का विमाजन है। अमेरिका के सविधान म 'विधि की उचित प्रक्रिया' वाक्याश के प्रयोग से सर्वोच्च यायालय की यायिक पुन-रीक्षण की शक्ति प्राप्त हो गयी है। विधि की उचित प्रक्रिया से तास्पय प्राकृतिक पाय (Natural Justice) के कुछ सबमाय सिद्धात्तो एव मापदण्डो से हैं। 'जी विधि इनके प्रतिकल होती है वह अमेरिकी यायालय की हृद्धि में असवैधानिक है।" अमेरिका म विधि की उचित प्रक्रिया' की कोई पूण परिभाषा कभी नहीं दी जा सकी है। इस शब्दावली क अभिप्राय सम्बाधी बहुत सी ब्यापक बातो पर सवसम्मत विचार हैं। 'विधि की उचित प्रत्रिया' के दो अब हैं अर्थात् पढ़ित सम्बंधी (procedural) और मूल सिद्धा त सम्बन्धी (substantive) । उदाहरणाय पदित की उचित प्रक्रिया (procedural due process) का फीजदारी विवादों म यह अय होता है कि अमियुक्त को अपनी रक्षा के लिए पर्याप्त कानुनी सहायता प्राप्त होनी चाहिए। बलप्वक प्राप्त स्वीकारोक्ति (confession) के आधार पर अपराधी की दिण्डित नहीं किया जाना चाहिए खुली अदालत में एवं निष्पक्षतापूर्वक विवाद पर विचार होना चाहिए इसके अतिरिक्त जिस विधि के आधार पर पास किया जास वह विधि भी तकसगत होनी चाहिए । यदि कोई विधि युक्तिसगत नही है या निरकुरा है तो यायपालिका उसे अवैध एवं निष्त्रमावी घोषित कर सक्ती है। 'विधि की उचित प्रतिया' निरकुशता, अतनसगतता एव अनौचित्य का विलोम है । किसी भी विवाद में इसका निणय यायाधीश ही कर सकता है कि क्या निरकुश और अनुचित है और क्या नहीं है। इसी आधार पर अमेरिका में यायिक सम्प्रमुता (judicial supremacy) के सिद्धात का विकास हुत्रा है। समुक्त राज्य अमेरिका म सविधान यही है जा यायाधीश कहते हैं। "किसी विधि की सवधानिकता एवं असवैधानिकता का निणय 'यायालय अपनी बौद्धिक एव सामाजिक घारणाओ के अनुसार करता है। इस प्रकार वह (अमरिकी सर्वोच्च यायालय) व्यक्ति स्वात त्र्य एव सामाजिक निय त्रण के बीच समुचित सातुलन स्थापित करने में समय है। 127

मारत में स्थिति इससे निम्न हैं। नारतीय सविधान में 'विधि की उचित प्रित्रमा' वाक्यारा का प्रयोग न बरके नवीन जापानी सविधान के आधार पर 'विधि द्वारा स्थापित प्रत्रिया' (procedure established by Law) वाक्यारा का

¹⁷ डॉ महादवप्रसाद शर्मा भारतीय गणत त्र का सविधान, 1959, वृ 223 24 ।

प्रयोग रिया गया है। इगस स्थिति मिश्र हो गयी हा अत दोना दशा के मर्वि धारा म एक मौलिक अत्तर है। मारतीय व्यायपालिका रो सिसी विधि भी वपा निरता. श्रीचित्य एव अनीचित्य पर विचार करन अथवा उस अवधानिक पापित करन मा अधिकार नही हैं बदातें सम्बर्धित विधि जिस विधानगण्डल (राज्य या संधीय) द्वारा पारित की गयी है उसकी विधायनी शक्ति एव क्षमता के बातगत है। इस स्पिति का एकमात्र अपवाद 'मौलिक अधिकारा स सम्बन्धित विधियाँ हैं। मौतिक अधिकारो पर ससद को बचल जनित या सर्वसमल (reasonable) श्रीतव प समान मा अधिकार है। सर्वोद्य "यायालय को ससद द्वारा मौलिक अधिकारा पर लगाय गर्य प्रतिय था क तकपूण होन का निणय सहज युद्ध (commonsense) एव नैसर्गिक-प्राकृतिक- याय के सिद्धान्ता (Principles of Natural Justice) क अनुसार' करने या अधिकार प्राप्त है। ¹⁸ स्पष्ट है हमार देवा में 'याविक सर्वोच्चता' नहीं है अपित एक प्रकार की सीमिल विधानमध्डलीय सर्वोच्चता (limited legislative supre macy) है । यदि विधानमण्डल अपनी सीमा अर्थात निविध्द वर्ति के अधीन विधि निर्माण करते हैं ता उनकी विधियों के असर्वधानिक घोषित किये जान का भय मही है। (अत) भारतीय सर्वोच्य यामासय पमरिकी सर्वोच्य यामालयकी माति विधान मण्डल का ततीय सदा नहीं बन सकता।"

सर्वोच्च यायालय का मृत्याकन

पारतीय सर्वोच्च वावात्य सरिवान एव मीतिन अधिकारो ना सरक्षक है। इसे केन्द्र एव राज्यो सम्बन्धी विवादो म मौतिक क्षेत्राविकार प्राप्त है। इस मानाव्य के द्वारा गायिक पुनर्रीक्षण की पत्ति का प्रयोग किया जाता है। यह देश का सर्वोच्च न्यायालय है। यह अपनी निप्पक्षता एव स्वन प्रता के लिए विदय का समित्रेष विवाद है। की सल्लावी कुष्णस्वाधी क्ष्या क अनुतार यह देश का अमित्रेष न्यायालय है। वेद व्यापक अधिकार सांच है। अपीत की विद्या अनु-भूति प्रवान करन की उसकी एक पर नोई सर्वेचानिक प्रतिव व नहीं है और इस सम्ब ध में उसे निपाय करने का पूण अधिकार है। यह कवन कि नारतीय मर्वोच्च यापालय नो विदय के सभी सविधानों से अधिक प्रयापक चर्तिया प्राप्त है, पूणत सम्म प्रस्त है। इस सम्ब ध म सरकाय म भारतीय एवं अपीरकार विवाद के स्वापल क्षारिकार प्राप्त है, पूणत स्वाप वी है। इस सम्ब ध म सरकाय म भारतीय एवं अमेरिकी स्वाप्त के स्वाप्त वी तलना रोचन एवं सिवाद है। यह निम्मवत है

 तपुक्त गच्च अमेरिका के सर्वोच्च वायालय को व्यापन पायिक पुन रिक्षण की व्यक्ति प्राप्त है। भारतीय सर्वाच्च यायालय की यह शक्ति अपक्षाकृत शीमित है।

¹⁸ डा महादेवप्रसाद क्षमी भारतीय वणतात्र का सविधान पृ 223 19 डा महादेवप्रसाद क्षमी भारतीय गणतात्र का सविधान, पृ 224

²⁰ पूच प्रध्ठो म तत्सम्ब धी विश्लेषण की देखिए ।

- (2) मौलिक अधिकारा की दृष्टि म अमेरिकी सर्वोच्च यायालय का क्षेत्रा-धिकार अपेक्षाकृत विस्तृत है। सध एव राज्यो के मध्य विवादा के अतिरिक्त उसे राजदूतो, मन्त्रियो, काउ सलरा, सिधयो, नौमेना, जलीय यातायात सम्ब धी विवादी म भी मौतिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। सारतीय सर्वाच्च यायालय को (क) सघ एव क्सी राज्य या राज्यो, (ख) सघ तथा एक राज्य या कुछ राज्य एक पक्ष हो एव एक मा कुछ राज्य दूसरे पक्ष म हो, तथा (ग) दो या अधिक राज्या के मध्य विधि सम्बाधी अथवा अप विवादो एव मौलिक अधिकारो की रक्षा के सम्बाध में मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है ।
 - (3) भारतीय मर्वोच्च यायात्रय को अमेरिकी सर्वाच्च यायालय की तुलना म अधिक पुतरावेदनीय क्षेत्राधिकार प्राप्त ह । मारतीय सर्वोच्च यायालय को संवधा-निक, भौजदारी, दीवानी एव विशिष्ट मामली में पुनरावेदनीय (appellate) क्षेत्रा-धिकार प्राप्त है। पुनरावेदन के लिए विनेष अनुमति प्रदान करने के उसे असीमित अधिकार हैं। ससद इस अधिकार म विद्व कर सकती है। अमेरिकी सर्वोच्च यायालय को केवल सवधानिक मामलो म ही पुनरावेदनीय अधिकार है। उसका पुनरावेदनीय क्षेत्राधिकार 1925 ई म पारित एवं 1937 ई म सक्षीचित क्षेत्राधिकार अधिनियम के अधीन सीमित एव निश्चित है। दीवानी एव अपराधिक विवादा म अमेरिकी सर्वोच्च यायालय को पुनरावेदनीय अधिकार प्राप्त नहीं है। अमेरिकी यायालय म निम्न अवस्थाओं म ही पुनरावेदन सम्मव ह (क) किसी राज्य के उच्च यायालय द्वारा किसी सिध को अवधानिक घोषित करने या किसी राज्य की निधि का संधीय सविधान या विधि या मिध के विपरीत ठहराने की व्यवस्था म, (ख) भ्रमणशील सधीय यायालय द्वारा राज्य-विधि को मधीय मविधान, विधि या सिंग के विपरीत टहरान की अवस्था म, तथा (ग) कम से कम 3 हजार डालर के हर्जान या क्षति स सम्बर्गित विवादी म । अमेरिकी सर्वोच्च यायालय म कुछ विवादा की अपीलें सीधे जिला यायालय से हा सकती हैं। उत्प्रेषण लेख के आदेश के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय राज्य-यामालया से एम विवादा की अपन समन्त मँगा मकता है जिनका सम्बाध सविधान की व्यवस्था या विसी विध की व्याव्या से होता है।

(4) अमरिकी सर्वोच्च यायालय शासन को विधिक परामग्न दन के लिए बाध्य नहीं है। कट्टर अमेरिकी विधिवेत्ताला की धारणा धी कि यापालय का काय उसक समक्ष उपस्थित वास्तविक विवादा में याय करना है, न कि कामपालिका को काल्पनिक स्थिति के सम्बाध म परामश या अपन विचार देना । अतः अमेरिको सर्वोच्च मायालय ने नामपालिका का निधि सम्ब धी परामदा दना सदैव अस्वीरृत निया है। लविन भारत म सर्वोच्च पायालय ना यह एक क्तव्य है एव राष्ट्रपति क द्वारा विसी विधि या प्रश्न के मम्बाध म परामश्च माँगन पर अपना मत दन क लिए सर्वोच्च "याया

लय बाध्य है।

भारतीय यायपालिका की स्थिति पर सर्वोक्त यायालय क यायाधार श्री एस आर बास न गोपासन बनाम महास राज्य विवाद म निणम दत हुए कहा पा कि "मारत म यायालया की स्थिति इगलैण्ड एव संयक्त राज्य अमरिका के मध्य की मारत म संयुक्त राज्य बमरिका के सर्वोच्च न्यायालय की नुमिका क तिए क्षेत्र नही है।" मौतिक अधिकारा की रक्षा के लिए 'यायालय की लख (writs) जारी वरने का अधिकार है। सहीय में, जनता की सर्वोच्च न्यायास्य में आस्या है । सर्वोच्च पायालय नागरिक अधिकारा की रक्षा के लिए सतत जा^{नहरू} रहा है एवं विवेक तथा सम्मानपुरक अपने दायित्व की सम्मादित करता है।

... स्यायाधीओ की स्वतस्त्रता

सर्वोच्च यायालय की स्वतावता हेत यह आवश्यक है कि यायाधीशा की नियक्ति एव पदच्यति सम्बन्धी पूण बक्ति कायपालिका या व्यवस्थापिका के अधिकार म नहीं होनी चाहिए। पदिनयस्ति के पश्चात यायाधीशों को पुन किसी पद पर निमुक्त नहीं किया जाना चाहिए। यायाधीशा के कायकाल, पदी नित एव इस्तान्तरण व सम्बाध में मनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए । भारत म यायाधीशो की नियुक्ति कायपालिका द्वारा की जाती है। सविधान निर्माताओं ने यायाधीया को नियक्ति की ब्यवस्था के साध्यम से अधिकाधिक स्वतं न बनाने का प्रमत्न किया है। उह काय पालिका द्वारा स्वेच्द्रापूवक पदच्युत भी नही किया जा सकता । यह महाभियोग बारा ही सम्मव है। लेकिन परीप्तित के मामला में वे पूरी तरह कायपालिका के हस्तक्षेप एवं प्रमाव से स्वतः क एवं मुक्त नहीं हैं। मुख्य यायाधीश के पद पर परीजित, उच्च ग्रायालय से सर्वोच्च यायालय म स्थाना तरण की सम्मावना एव पदिनवृत्ति के पहचात कायपालिका की कुपा-दृष्टि के कारण यायाधीश से अनुचित या पक्षपातपुण आचरण की सम्मावना हो सकती है। अनुच्छेद 126 के अनुसार कायकारी मुस्य मामाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था है। परातु कामकारी मुख्य यायाधीश से काम-पालिका से पण स्वत वतापुर्वक काय करने की आज्ञा असम्मव नहीं तो सादेहजनक अवस्य है । मुख्य "वायाधीश की नियक्ति की लेकर एक विवाद 1973 ई में उठा था। दो वरिष्ठ यायाधीको-- मायमूर्ति ग्रोवर एव हेगडे-की उपेक्षा करते हए 'यायमूर्ति सीकरी के मुख्य यायाधीय पर से अवकाख ग्रहण करने पर श्री ए एन राय की राष्ट्रपति ने मूक्य यायाधीश नियुक्त कर दिया था। इस नियुक्ति की तीव आलोधना हुई है और यह तक दिया गया है कि इससे याया नीशा म शासन को प्रसन करने की प्रवृत्ति विकसित हो सकती है। इससे वरिष्ठता के सुस्यापित अभिसमय का उपालन हमा है। वार काउ सल ने भी इस नियुक्ति के विषद प्रस्ताव पारित किया था। निस्स देह न्याया धीशों की नियक्ति में इस प्रकार की घटनाए दू खद एवं "यायपालिका की प्रतिष्ठा एवं स्वत त्रता के प्रति जन-आस्या को हिलाने वाली होती हैं। परातु इस प्रकार की घट नाओं की पनरावत्ति को रोकने के लिए यह वाखनीय है कि न्यायाधीओं को भी परि

वितित सामाजिक आधिक व्यवस्था एव सामाजिक दशन को व्यान मे रखते हुए सस्तीय विधियों की व्यास्था करनी चाहिए । जब यायपालिका सामाजिक परिस्थिति के अनुकूल सविधान एव विधियां की व्यास्था में असफल रहती है और नीरस तथा गुष्क विधिकता का शिकार होकर उनकी व्यास्था करती है तो सवधानिक सशोधन अनिवाय ही चाते है और कभी कमी कायपालिका को यायपालिका के सुधार हेतु कदम उठाने पहते हैं। राष्ट्रपति फ्रेंकलिन ही स्ववेल्ट का अमेरिकी सर्वोच्च यायालय के यायपायीयों की नियुक्ति सम्बंधी प्रस्ताव ऐसा ही एक प्रयास था। भारत में सर्वोच्च यायालयों को पत्र मुक्ति के पश्चात मंत्री, राज्य पाल, राजवृद्धों तथा विभिन्न आयोगा के अध्यक्षों के पद पर नियुक्त किया जाता रहा है। यह यायिक स्वत त्रता की दिन्दि से उचित नहीं है। को की विधान विभिन्न आयोगा के अध्यक्षों के पद पर नियुक्त किया जाता रहा है। यह यायिक स्वत त्रता की दिन्दि से उचित नहीं है। को के बी राव³¹ ने याया-धीका की निष्कक्षता एवं स्वत त्रता की रिक्षा हेतु निम्न सुकार दिये हैं

(1) राष्ट्रपति द्वारा समी यायाधीक्षों की नियुक्ति एक सूची में से की जानी चाहिए।

(2) सर्वोच्च तथा उच्च यायालय के सभी पायाधीशों को समान वेतन एव मत्ता दिया जाना चाहिए। मुख्य यायाधीशों की नियुक्ति वरिस्ठता के आधार पर कमवार होनी चाहिए। मुख्य यायाधीशों को अप पायाधीशों से केवल पद सम्बाधी मत्ता अधिक दिया जाना चाहिए।

(3) सभी यायाधीशों को सविधान में व्यक्त महाभियोग की रीति से ही

पदच्युत किया चाहिए।

(4) पर निर्वात के पश्चात करीब करीब बेसन के बराबर ही पैशन दी जानी चाहिए।

(5) यायाधीयो को पद निवस्ति के पश्चात देश की राजनीति म भाग नद्दी लेना चाहिए, न उन्हें किसी कायपालक पद पर ही नियुक्त किया जाना चाहिए, न उन्हें अपने कायकाल के दौरान कायपालिका एवं नेताओं की प्रशसा करनी चाहिए और न किसी ताल्वालिक राजनीतिक प्रशन पर उन्हें अपने विचार ब्यक्त करन चाहिए।

उपरोक्त सभी सुभाव अत्यन्त सामियक हैं एव इनके अनुवसन से यापपानिका की स्वत नता एव प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण रखने म निस्स देह सहायता मित्तगी।

30

निर्वाचन एव प्रतिनिधित्व [ELECTIONS AND REPRESENTATION]

आधुरिक युग लोकतात्र का युग है। प्रत्यक्ष लोकतात्र जिसम जनता स्वय शासन करती है, आधुनिक युग में असम्भव एवं अन्यावहारिक है। स्विटजरलैण्ड एवं सयक्त राज्य अमेरिका के बुखेन राज्यों में आधुनिक काल में प्रत्यक्ष प्रजात श्रीय व्यवस्था पायी जाती है। अत प्रतिनिधि या अप्रत्यक्ष लोकता व ही लोकता व ना वतमान काल मे प्रचलित एवं स्वीकाय रूप है। इसम जनता अपने प्रतिनिधियों को एक निविचत अवधि के लिए निर्वाचित करती है और जनता के प्रतिनिधि जनना के नाम पर शासन करते है । मिद्धा तत जनता अर्थात् निवाचव - सम्प्रम् है । उ हे 'राजनीतिक सम्प्रम्' भी नहतं हैं। बतमान समय में लोकतात्र से तात्वय प्रतिनिधि शासन या उत्तरवायी हासन से है अर्थात शासन प्रतिनिधियो द्वारा किया जाता है और वे अपने कार्यों एव नीतियों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रतिनिधियों का किस प्रकार निर्वा चन हो और कौन उनको निर्वाचित करे अर्थात् निर्वाचन एव मताबिकार प्रजात न नी महत्वपण एव जटिल समस्याएँ है। प्रतिनिधि की निर्वाचित करने वाले व्यक्तिया की सामृहिक रूप स मतदाता या निर्वाचक (Elector or Voter) एव प्रतिनिधि निर्वा चित करने के अधिकार को मताधिकार कहते हैं। मताधिकार राजनीतिक अधिकारो म सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार है। प्राय सभी लोकता निव दशा म एक निविचत आयु-सीमा के पार करने पर स्वस्थ चित्त एव देश के स्थायी निवासियो अर्थात नाग रिको को मताधिकार प्रदान किया जाता है।

आयुनिन लोकत त्रीय राज्यों में मतदाता की स्थिति के द्रीय है। अतत वे ही राज्य एवं शासन का स्वरूप निष्ठित करते हैं। सविधान उनकी इच्छा की अभिध्यक्ति हैं और शासन का निर्माण एवं सवासन उनके निर्देशन पर होता है। निर्वावका द्वारा प्रतिनिधि चुने जात हैं और वे शासन का निर्माण करते हैं। वे विधानमण्डन के सदस्य होते हैं। विधानमण्डन द्वारा ही सम्पूण धासनत न को सचालित एव व्यवस्थित हिया जाता है। कुछ दसा म विधानमण्डल के सदस्या वो निवाजिन करन क अलावा मत-वाताओं द्वारा अन्य प्रधासकीय एव न्यायिक अधिकारियों को भी चुना जाना है। अत मनदाताओं को राज्य के सिनय नागरिका के निकाय की सना द सकते हैं। प्रतिनिधि तोवत य या जन सासन निम्न सीन वाता पर निकर हैं।। भताधिकार किन व्यक्तिया को प्रदान निया जाय? (2) राज्य द्वारा मतदाताओं पर कौन से प्रतिव ध न्याय जाते हैं? एवं (3) मतदाताओं तथा सासन म क्या सम्ब प हैं?

मताधिकार

आधुनिक लाकत या में वयहरू मताधिकार का सिद्धा त मा प है। इसने अधीन प्रत्यन वयहरू हनी पूर्व पूर्व को मताधिकार प्राप्त होता है। मताधिकार मम्ब धी उन पर अन्य कोई प्रतिव घ नहीं होता। फेन नाित के निजारक मताधिकार मम्ब धी उन पर अन्य कोई प्रतिव घ नहीं होता। फेन नाित के निजारक मताधिकार माम माम प्रत्य का प्राष्टित अधिकार माम के हनी होता। के लिए नितात जानस्यक है। समाज के सदस्य के रूप म स्यक्तिक का सामाजिन व धना को हनीनार करना पहता है। वह स्वय तो अपना धासक नहीं हो मक्ता परन्तु उमे स्वय अपने हासका में निविध्य करने मा अधिकार तो होना ही चाहिए। इस अधिकार के अमान म उसकी स्वत नता का नोई मूल्य नहीं है। यह समाप्त हो जाती है। अस मताधिकार स्वत नता प्राप्तिक ले एक अपिहार सही है। यह समाप्त हो जाती है। अस मताधिकार स्वत नता प्राप्तिक ले एक अपिहार साधन है। इस इंटिट से यह एक प्राकृतिक क्यांत अनिवाय एव अवक्षयत्व अपिकार जहीं व्यक्तिक एव नितक मांग होती है नहां वह समाज की स्वीकृति के परचात हो यथा कर म अधिकार का रूप धारण करता है। तम मनाधिकार का प्रयोग प्रत्यक व्यक्तिक हो विकानुमार समाज हित म हो करना चाहिए। इस इंटिट से मताधिकार एक सामाजिन और नितक करत्य तथा दाविस्व है।

प्राचीन एव मध्य युग मे वयस्क मताधिकार का मिद्धारा प्रचितिन मही था। प्रमाणि एव रोमन काल म जनजातीय आधार पर मताधिकार की व्यवस्था थी। मध्य युग मे मताधिकार केवल धनी भू स्वामिया को ही प्राप्त था। बाधुनिन पुग के प्रारम्भ म तिवता सिद्धार्त के किलस धनी भू स्वामिया को ही प्राप्त था। बाधुनिन पुग के प्रारम्भ म तिवता सिद्धार्त के किलस के फलस्वरूप प्रयोक व्यक्ति को मताधिकार का किल किला को प्राप्तिपादन किया गया और आधुनिन युग म ही मताधिकार का किल किला देन के प्राप्तिनिधि प्रणाली के विकास के सदम में निम्म विचार व्यक्त किय हैं। अनता रूपी सामाय निकाम के प्रतिनिधिया के लिए मत देने के अधिकार ना आधार थेट प्रिटेन एव अमेरिका की स्वतान सस्माएँ है। इन प्रतिनिधि सस्थाओं की उत्पत्ति के अकुर प्रारम्भिक वाल सस्सन सस्था सिद्धार पर है। समनत कालीन इनलण्ड म प्र येक कस्व द्वारा व्यासा प्रतिनिधित करने के लिए एक निर्वाचित रोवी (recve) एव चार व्यक्ति दरवार या द्वायर (Shuse) की सामाय समा में भेजे जाते थे। अनुमानत इसलण्ड म हर स्वत व व्यक्ति को प्रारम्भिक निर्वाच्या म मां में वेज नाते व व्यक्ति राज्यान समा समा

858 | आयुक्तिक पासनत त्र न्न स्वामिया तक ही सोमित था । 15वा सती क इयलण्ड जस दश म जहाँ सम्पत्ति,

सामाजिक स्तर एव भू स्वामित्व समानार्थी यान जात थे, एसा हाना स्वामाविक भी पा। हेनरी चतुष क नाल म एक विधि द्वारा गाउण्टी निर्वाचना म 40 सिविष प्रति विधा मान स्वामाविक भी विद्या मान स्वामाविक भी विद्या स्वामाविक भी स्वामाविक स्व

मागरिका म केवल उन व्यक्तिया को शामिल किया गया या जो प्रति वय अपन तीन

दिन के श्रम के बराबर प्रत्यक्ष कर देते थे।"३

चेट बिटेन औद्योगिक वृत्ति एव नेपोलियन के युद्धों के फलस्वरूप 1832 ई म इगलण्ड मे मताधिकार सम्बाधी प्रथम सुधार किये गये। काम स समा के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रथम बार पुणक्येण पून वर्गीकरण किया गया था और उन सभी व्यक्तियों को मताधिकार प्रदान किया गया जो 50 पीण्ड प्रति वय लगान की भूमि के स्वामी थे। इसके फल स्वरूप प्रथम बार मध्यम एव उच्चवर्गीय सदस्यो की सताधिकार प्राप्त हुआ या। 1867 ई म मताधिकार म पुन बृद्धि की गयी एवं बरो (Borough) के प्रत्येक सकान मालिक या 10 पीण्ड प्रति वय लगान के पटटे की भूमि के मालिक या 12 पीण्ड व्यक्ति सकात के किरायदारा की मताधिकार प्रदान किया गया था। 1884 ई के ततीय सधार विल के द्वारा मताधिकार की व्यवस्था का और अधिक उदार वनाया गया। 1918 ई में मताधिकार सम्बाधी यहे व्यापक सुवार किय गये थे और सम्पत्ति सस्य थी सभी योग्यताएँ समाप्त कर दी गयी थी। सिद्धा तत हिनयो को हगलण्ड म प्रथम बार मताधिकार देना स्वीकार किया गया लेकिन 30 वर्ष और उसस अधिक आय की स्नातिकाओं तथा गृह स्वामिनिया को ही मताधिकार प्रदान किया गया था। 1929 ई मे सभी स्त्रिया की मताधिकार प्रदान किया गया और इस प्रकार इंगलण्ड मे पुण मताधिकार की स्थापना हुई थी।

सपक्त राज्य अमेरिका

अमेरिका मे मताधिकार का निर्धारण राज्यों के क्षेत्राधिकार के अत्तयत है।

¹ Leacock Elements of Political Science, 1929, pp 209 210

प्रारम्म म प्रत्येक अमेरिकी राज्य मे मताधिकार सम्पत्ति पर आधारित होने के कारण भूमि या मकान के स्वामियों को प्राप्त था। 1820 से 1840 ई तक अमेरिका में प्रवाहित लोकताित्रक विचारों के तीन्न प्रवाह के फलस्वरूप वहा वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई थी । स्त्रियो को सवप्रथम मताधिकार व्योमिम (Wyoming) नामक क्षेत्र मे प्रदान किया गया या और वीरे-घीरे सभी राज्यो न इसका अनुसरण विया। 1911 ई म काग्रेस द्वारा सविधान में एक सक्षीधन प्रस्तावित करके प्रत्येक जगह स्त्रियों को मताधिकार दिया गया था। इस सशोधन की आवश्यक सरमा मे राज्य विधानमण्डला ने 1920 ई में स्वीकृति प्रदान की थी और उसके पश्चात ही यह संशोधन प्रमानी हो सका । संयुक्त राज्य म 1856 ई तक केवल गीरे पुरुषी की ही मताधिकार प्राप्त था। नीग्रो (काले) लोगो के लिए मताधिकार का माग अमेरिकी गह्युद्ध के परचात 15वे एव 16वे सशोधनी द्वारा खोला गया एव 1867 ई मे दक्षिणी राज्यों के नीग्रो लोगों को काग्रेस की विधि द्वारा मताधिकार प्रदान किया गया था। 1870 ई के 15वें सशोधन द्वारा अमेरिकी नागरिक के साथ जाति, रग एव दासता के आधार पर मताधिकार सम्बाधी विभेद को निषिद्ध घोषित किया गयाथा। कई राज्याने नीग्रो लोगो पर आवासी एव पौल कर (Poll Tax) सम्बद्धी प्रतिबद्ध लगारखेथे। आज यद्यपि नीग्रो जाति को मताधिकार प्राप्त हो गया है और इस अधिकार के सरक्षण की उनम तीव चेतना भी है पर तु खेत जाति द्वारा उन्हें मतदान से पृथक रखने का प्रयस्त किया जाता है। अमेरिका में अभी तक मताधिकार 21 वर्षीय नागरिक को ही प्राप्त था परातु काग्रेस ने जायु सीमा को घटा-कर 18 वयं कर दिया है।

स्विटजरलण्ड

आधुनिक काल में स्विटाज्यसम्बद्ध को प्रत्यक्ष लोकतान की पाठ्याला महा जाता है। मताधिकार कैण्टाने के क्षेत्राधिकार के अत्तयत है। 1971 ई तक स्विट जरलैण्ड में केवल यसक पुरुष मताथिकार प्रवस्तित था। स्त्रियाको मताधिकार केवल इसी वप दिया गया है।

फास

1810 ई में फ़ास म राजतान की पुनस्यीपना के फलस्वरूप 300 कर वापिक कर दने वाले 30 वर्षीय पुराम को ही मताधिकार प्रदान किया गया था। 1830 ई की नाति के परवात 300 फेंक की राशि को घटाकर 200 फेंक कर दिया गया। 1840 ई में फ़ास म सावयोग मताधिकार के लिए आ दोलन प्रारम्म हुआ और 1848 ई में इसे सफ्सता प्राप्त हुई। द्वितीय गणराज्य की स्थापना पर फास में प्रत्ये प्रता मार्थिकार की स्थापना की गयी और प्रत्ये 21 वर्षीय प्रता में प्रत्ये एवं साविकार की स्थापना की गयी और प्रत्ये 21 वर्षीय प्रता ने नातिक को मताधिकार प्रता की स्थापना की गयी और प्रत्ये 21 वर्षीय प्रता की गयी और प्रत्ये 21 वर्षीय प्रता की गयी और प्रत्ये 21 वर्षीय प्रता की गयी और प्रत्ये वास की गयी की प्रत्ये वास की गयी की प्रता की गयी की प्रत्ये वास की गयी की प्रता की गयी की गयी

अन्य वेश

पुर समय पून नव गूराव ने निमिन्न दशा म मताधिवार पर अनन प्रतिव य । 1871 ई ने साम्प्राज्ञयीय जान से सविवान न अन्तनत समस्त 25 वर्षाय पुरुष नागरिका रा न द्वीय मदन रीस्टाव के लिए मताधिकार प्राप्त था । पर तु राज्य निर्माण के साम प्रता के लिए मताधिकार प्राप्त था । पर तु राज्य निर्माण के अप्रत्यक्ष था । आस्त्रिय । 1907 ई तथ निम्म सदन ने नेवल कुछ सदस्य ही सावमीम मताधिकार पर पूर्व जाते थे । हमशे म मताधिकार सम्पत्ति, कर युव तिक्षा सम्बन्धी जटिल योग्यताओं पर आधारित था । नार्षे म 1898 ई म वयस्य मताधिकार प्रारम हुआ था । वेत जिलम म 1893 ई तक मताधिकार पर सम्मित सम्ब थी मारी प्रतिव ध वे । 1912 ई म इटली म मताधिकार के लिए कर दंग एव तिक्षा सम्ब पी योगवाएँ प्रचित्त थी । जावान म 1925 ई तक मताधिकार न लिए कर सम्ब पी योगवाएँ प्रचित्त थी । जावान म 1925 ई तक मताधिकार न लिए कर सम्ब पी योगवार प्रचित्त थी । जावान म 1925 ई तक मताधिकार न लिए कर सम्ब पी योगवार प्रचित्त थी । जावान मे 1927 ई में वाचान में प्रवान स्वर्ण मताधिकार प्रवान तथी । गावीन सिव्यान म वयस्क पुत्र सावभीम सताधिकार की काई मता धिकार प्राप्त नही था । गवीन सिव्यान म वयस्क एव सावभीम सताधिकार की क्यतस्या है । प्रदेक 20 वर्षीय जावानी नागरिक नो सताधिकार प्राप्त है लेकन उस निवासन स्वेत्र म तीन माह के निवास सम्ब थी योगवार की पूल करना परवात है ।

सोवियत कस में 1936 ई क सर्विधान के अन्वयत पूर्ण वयस्क मताधिकार की स्थापना की गंधी है। इसके पूज प्रचलित समस्त विभेदकारी निवमा का समान्त कर विया गया है। प्रत्यक 18 वर्षों व धोनियत नागरिक को विना क्सि भेदमान क मताधिकार प्राप्त है। प्राप्त एव दण्डित नागरिक इसके अपवाद है। मशहर सनाजा के सहस्या का भी मताधिकार एवं निवांचित होने का अधिकार है।

सास्यवादी चीन म किसी भेदमाव के बिना प्रत्येक 18 वर्षोय वयस्क स्त्री एव पुरुष नागरिक को जो पागल न हो और जिसे किसी विधि द्वारा इस अधिकार स विचत म किया गया हो, मताधिकार प्राप्त है।

भारत क गणतानीय सविधान (1950 ई) द्वारा वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गयी है। प्रत्यक 21 वर्षीय भारतीय नालरिक को बिना किसी भेदमाव के मताधिकार प्रान्त है। स्वत नता के युव भारत म मताधिवार सम्बन्धी साम्प्रदायिक, मामित एव शक्षणिक सम्बन्धी व्यवस्थाए वी वि ह स्वत नता के परचात पूणक्ष्यण समान्त कर दिया गया है।

उपराक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि सावभीभ वयस्क मताधिकार (Univer sal Adult Franchise) शाय सभी देशा द्वारा स्वीनार किया जा जुका है।

² Garner Political Science and Government 1951, pp 510 511

पक्ष में तक निम्नवत है

- (1) प्रत्यक व्यक्ति को शासन के निर्माण म अधिकार प्राप्त होना चाहिए। सभी व्यक्ति प्रकृति से समान एवं स्वतात्र है। जत किसी व्यक्ति या व्यक्ति-समूह को रोप व्यक्तिया पर विना उनकी सहमति के शासन का अधिकार नहीं होना चाहिए। सामाजिक समफीताबारी विचारक प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धात के आधार पर सावभीम मताधिकार का समयन करते थे। व्यक्तित्व क पूण विकास के लिए साव-भीम मताधिकार एक अनिवाय शत है।
 - (2) जॉन स्टुअट मिल का यह मत था कि किसी व्यक्ति को सावजनिक मामला क सम्पादन म अय व्यक्तिया की मीति उसके सम्पादन के अवनर न देना उसका अपमान करना है। यदि किसी व्यक्ति को कर देन अववा युद्ध करने के लिए वाच्य किया जाता है तो उसे विधिक रूप से यह जानने का भी अधिकार है कि वह अयो सडे एव पयो कर दे हिस के अतिरिक्त उससे भी स्वीङ्गित तथा परामश लिया जाना चाहिए।
 - (3) यदि कुछ व्यक्तिया को मताथिकार नहीं दिया जाता है तो यह सम्मव है कि दियानमण्डल उनके हितों की उपक्षा कर दे।
 - (4) सीमित मताधिकार के फलस्वरूप राजनीतिक समानता के सिद्धा त का
 - सहज ही अतिक्रमण हो जाता है। (5) सावसीस सताधिकार के फलस्वरूप विद्रोहो एव कारिया की सम्मावना
 - समाप्त हो जाती है । (6) सावभौम महाधिकार क फलस्वरूप नायरिको की सावजनिक कार्यो भ रुचि उत्पन्न होती है और उनके अनुसव एव आस्मसम्मान में विढि होती है ।

विपक्ष में तक —लेकिन सावभीम मताधिकार का विरोध भी कम नहीं हुआ है। लोकत न के समयको ने भी सीमित मताधिकार का समयन किया है। सावसीम मताधिकार के विपक्ष म निम्नलिखित तक प्रस्तुत किये जाते हैं

लाइ मकाले (Lord Macaulay) को इससे ब्यायक अपहरण प्रारम्म हो जान का सथ था— 'कुछ अद्धनक मुद्दोने पूरोप के महानगरो के व्यसावधोपो को पूर्वी (उल्लुओ) एव चालाको (लोमहियो) के साथ बाटकर सा जामेंगे। लेको (Lecky) का मस था कि इससे ज्यानियो के शासन की आश्वका बढ जायेगे। जेमस स्टीफेन का नस था कि सावभीम मनाधिकार के फ्लम्बरूप विनेक एव मुस्ता के सही एव स्वामाविक सम्बाध के उसट जाने की सम्यावना है। सर हेनरी मेन (Sir Henry Maine) भी सावभीम मताधिकार के विरोधी थे। ईसाइल लेकने (Emile Lava

³ Mill Representative Government, Ch VIII

leye) के अनुसार अञ्चानिया को मताधिकार दन का अब आज अराजकता तवा का निर्देशता म प्रमा है। अब इन विद्वाना ने सीमित मताधिकार का समयन किया या । सावभीम मलाधिरार का प्रसार निविरोध नहां हुआ है । पश्चिमी देश म स्थिया को मताधिकार 20वी सदी म दिया गया है। ब्रेट ब्रिटेन म 1918 ई मस्ब प्रयम 30 वर्षीय या उसस अधिक आयू की स्त्रिया की मताधिकार प्रदान किया था। सौमाग्य स स्वतात्र नारत य सावगीय मताधिकार की प्रारम्भ स ही स्वीकार कर लिया गया है।

स्त्री मताधिकार के समयन में अनेक तक दिये गये हैं। इनमें से कुछ निम्न लिपित हैं

(1) लिंग भेद से मताधिकार का कोई सम्बंध नहीं है।

(2) स्थिया को धारीरिक हृष्टि से बमबीर होने के बारण कानन एवं सामा (3) राजनीतिक जीवन म स्थिया का प्रवेश राजनीति को शद्ध एव परिष्कृत

जिक सरक्षण की अपेक्षाकृत अधिक आवश्यक्ता है।

करने में सहायक होगा । मताधिकार 3 देने का अब समाज को उसके लगमग आधे सदस्या की योग्यताना तथा गुणा से विचत कर देना है। (4) पूछ्यो के अत्याचार से उननी रक्षा हेतु स्थियो को मताधिकार देना

अपक्षित है।

(5) स्त्री पृद्ध में विभेद अनैतिक है तथा समता के सिद्धा व के विरुद्ध है। अत स्थियों को मताधिकार दना एक नैतिक आवश्यकता है।

स्त्री मताधिकार का समधन जान स्टबंट मिल सिजविक एवं एस्मिन आदि

केंद्रका ने किया है। जान स्टबंट मिल स्त्रिया की स्वत त्रवा तथा मताधिकार का तीव समयक था । स्विटजरलैण्ड में स्त्रिया की मताधिकार 1971 ई म ही प्रदान किया गया है।

सावभीम मताधिकार के प्रति व्यक्त अधिकास आशकाएँ निमृत सिद्ध हुई हैं। फिर भी सावभीम मताधिकार के दोषों को कम करने के लिए वहल मतदान (plural voting) एव अतिरिक्त मताधिकार प्रणाली (Weightage System) का प्रयोग किया गया । मिल ने मतनान के सम्बाध में साक्षरता एवं बर देने सम्ब धी घीग्यताएँ निर्धारित करने का प्रस्ताव किया था। उसका यत या कि जो व्यक्ति पढ लिख नहीं सकता एव प्रारम्भिक गणित के प्रश्न इल नहीं कर सकता, वह मतदान का अधिकारी नहीं माना जा सकता है। मिल तो विश्व की प्राकृतिक एव राजनीतिक सरचना एवं विमा जन तथा सामा य इतिहास ना कुछ ज्ञान भी यतदान के लिए आवश्यक मानता था।

⁴ Refer to E Assevatham op al, pp 415 16. Garner pp 511 13

⁵ Mill Representative Government, pp 160 162



(4) निर्वाचन क्षेत्रो का निर्माण किन आधारो पर होता चाहिए ?

निर्वाचन से सम्ब िवत एक विवादास्पद प्रश्न यह है कि वह प्रत्यक्ष होना

(5) अल्पसरयका के प्रतिनिधित्व की समस्या ।

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन

चाहिए या अप्रत्यक्ष । मतदाता स्वय मतदान करके जब अपन प्रतिनिधिया को निर्वा वित करता है तो इस पढित को प्रत्यक्ष मतदान (Direct Election) कहत हैं। इसके विपरीत मतदाता अपने प्रतिनिधिया को निर्वाचित करते के लिए मध्यवीं निर्वाचित करते जाता है नो इसे अप्रयक्ष निर्वाचित (Indurect Election) कहत हैं। प्राप्त विश्वक सभी देशों के विधानमध्यक के निम्म सक्तों के सदस्यों को प्रत्यक्ष रीति स निर्वाचित विया जाता है। समुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित विया जाता है। समुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित विया जाता है। समुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट प्रत्यक्ष रीति से समानुपातिक प्रतिनिधित के आधार पर चुनती है। इनके विपरीत आय मभी दितीय सदन प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित या ममोगीत होते है। उत्यत्वच्य के लिए, कात की काउ साल, दक्षिणी अफ्रीका की सीनेट, आयरक्ष की सीनेट मारत की राज्यक्षणा, सोवियत कस की राज्यक्ष प्रतिक स्वत्यक्ष की लाइ साम व्यानुपत एव मनोनीत है। काज का दितीय सदन है। के किन इनकण्ड की लाइ साम व्यानुपत एव मनोनीत है। काज का दितीय सदन स्वीन निर्वाचित होते हैं। काज का दितीय सदन निर्वाचित होते हैं। काज का दितीय सदन निर्वाचित कर की राज्यक्ष राज्य है अ जाते हैं। काज का दितीय सदन निर्वाचित होते हैं। काज का दिवीय सदन निर्वाचित होते हैं। काज का दिवीय सदन निर्वाचित होते हैं। के जाते हैं अव वे अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित होते हैं। है।

प्रस्काक निवादिन पद्धित लोकतात्र का पर्योववाची है। लेकिन जान स्टुअट मिल सहरा बिद्धानों को बुद्धिमत्ता, साधारण जनता की योग्यता तथा विवेदशीलता म पूण विद्यास नहीं है। वे लाकत त्र म अवात के अत्याचार से आतिक्ति हैं। अत लोक तत्र म सावभीमिक नातिधिकार के यथाय एव सम्मावित दोयों को दूर रूर रूक लि निवादिन का अत्रत्यक्ष एव प्रत्यक्ष पद्धित्यों म विमाजित करन का व ममपन करते हैं। अप्रत्यक्ष निवीचनों के पक्षपर अपने समयन म यह सवल तक प्रस्तुत करते हैं कि

समा मी अप्रत्यक्ष रीति स निवाचित सदन था।

⁷ अमरिकी सीनेट 1913 ई के पूज तक अब्द्यस रीति ॥ निर्वाचित सदन या। प्रशा का जिन्न सदन एवं 1905 ई कं पूज नाव का एक सदन स्टाधिंग (Storthus) अब्दायस रीति से निर्वाचित होता या।—Garner Political Science and Government, op ct, p 529

⁸ भारतीय द्वितीय सदन — राज्य समा— ने 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हात हैं।

हात है।

निपात का एकमात्र सदन 'राष्ट्रीय पत्रायत' क सदस्य अत्रत्यक्ष रीति स निर्वाचित

क्रिय जात है। पाक्स्तान म जनरत अपूत्र के समय म मठिन सदन 'राष्ट्रीय

विधायको ने दायित्वा की हृष्टि स यह आवश्यक है कि उनका निर्वाचन सामा य नागरिका स अधिक योग्यता सम्पन व्यक्तियो द्वारा किया जाना चाहिए। उनकी सरया भी कम होनी चाहिए जिससे कि वे सामा य जनता के उद्धेग एव भावना से मुक्त रह सकें। उन्हें सामान्य नागरिक नी अपेक्षा अधिक उत्तरदायी सजग एव बुद्धिमान होना चाहिए। ऐसे निर्वाचनों के द्वारा निर्वाचित विशानमण्डल निस्म देह अधिक उत्तर-दायित्वपूवक नाम करेंगे। 10

लेकिन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के उपरोक्त तकाँ के विरुद्ध अनक तक प्रस्तुत किये जात हैं और सिद्धा तत इससे अपेक्षित लाम प्राप्त नहीं हुए हं

- (1) अत्रत्यक्ष प्रणाली के अतगत मतदातागण राजनीतिक शिक्षा से विचत हा जात हैं और उनम सावजनिक सावना का पूण विकास नहीं ही पाता है।
 - (2) मह पढित प्रत्यक्ष निर्याचन पढित की अपेक्षा जटिल है।
- (3) मध्यवर्ती निर्वाचका की सरया कम होने के कारण उनक भ्रष्ट होन, तथा रिश्वत, छल कपट एव दबाव में सरलतापूचक प्रमासित होने की अधिक सम्मा वना रहती है। मध्यवर्ती निर्वाचका का कोई स्थायी पद नहीं होता। उन्ह अधिक हानि का मय नहीं है, अधिक से अधिक वे पुन निर्वाचित नहीं हो सकते। अत उनक भ्रष्ट होने की अधिक गुजाइश्व होती है।
- (4) अप्रत्यक्ष निर्वाचन-प्रणाली लाकत तीय सिद्धात के विपरीत है। जनता चूकि अतिम रूप म अपने प्रतिनिधि को चुनने म असफल रहती है अत जनता की निर्वाचना म कोई आस्था नहीं रहती।
- (5) गामर के अमुसार सुसगठित एव सुदृढ राजनीतिक दला व उदय एव विकास के कारण अप्रत्यक्ष निर्वाचन नाममात्र के लिए ही अप्रत्यक्ष होता है। 11 'मध्य वर्ती निषाचना' के लिए दलीय प्रत्याधियों को खड़ा किया जाता है और विजयी हाने पर वे अपने दल क प्रत्याधी के लिए ही मतदाग करत हैं। उदाहरणाय, समुक्त राज्य अमरिका के राष्ट्रपति एव उप राष्ट्रपति यह के सम्बर्ध म यह पूणत स्पर्य है। मारत म राष्ट्रपति के निवाचन म निर्वाचक मण्डल क सदस्य दलीय प्रत्याधी को ही अपना मत देते हैं। अत दलीय य्यवस्था के विकास के कारण अप्रत्यक्ष निर्वाचन वेवन सवधानिक व्यवस्था मात्र वन कर रह गया है।

गुप्त या सावजनिक मतवान

निर्वाचन से सम्बंधित एक बाय प्रश्त यह है कि मतदान गुप्त या मावजनिक या सूचा (public or open) होना चाहिए। गुप्त मतदान (vote by ballot) आजकत्त सबमा य एव स्वीकृत सिद्धात है लेकिन सदैव ऐसा नहीं या । मावजनिक

¹⁰ Mill Representative Governments, p 294

¹¹ Garner op cut p 531

मतदान 20 भी सदी के प्रारम्भ तक वेवल कुछ देशां म (यथा—डेनमाक म 1901, प्रसा म 1920, एव सोवियत रूस म 1936 ई तक) ही प्रचलित या। 1914 ई तक फ्रास म भी पूरी तरह गुरु मतदान प्रणाली प्रचलित नहीं थो। मिल, मोर्टेस्क्यू एव ट्रीटस्के सावजीनक मतदान के प्रधापती थे। 18थी तथा 19थी तदी म गुप्त मत दान की प्रया नहीं थी। यो टेस्क्यू ने सावजीनक मतदान का समयन इस आधार पर किया या कि इससे सामाय व्यक्ति को अपने मत के प्रयोग म अपेशाकृत योग्य एव बुद्धिमान व्यक्तियों से सहायता एव निर्देश प्राप्त हो खकेगा। 12 मिल ने इसका सम थन करते हुए कहा कि मतदान सम्याधी कतव्य अप सावजीनक कतव्यो की मौति सावजित कालोचना एव वेखमाल में ही सम्यादित किया जाना चाहिए। 12 ब्री ट्रीटस्के के लमुसार 'पुष्त मतदान उचारवाद के नाम पर वास्तव म एक घोता है।" यह अनुसित एव अनैतिक है। मतदान उचारवाद के नाम पर वास्तव म एक घोता है।" यह अनुसित एव अनैतिक है। मतदान एक सावजितक कतव्य है और इसका प्रयोग मो सावजितक एम म ही विचा जाना चाहिए। ऐसे किसी व्यक्ति को सच्च अवों म राजजीतिक सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता जो सवपटी के पास पहुँच कर मत दते समय (अपन मताविकार के मलत प्रयोग के लिए स्वयं का) अपमानित महसूस नहीं स्रका। 14

सावजिक मतदान वा सबसे बढा बोप यह है कि मतदासा निर्मोक्तापूषक अपनी इक्छानुसार स्वत प्रतापूषक अपने मत का सावजिक रूप से प्रयोग नहीं कर सकता है। सीकतान के वाष्टिय सहसा की प्राप्त के लिए स्वत प्रता एवं निर्मोकतापूषक मताभिकार का प्रयोग वाष्ट्रनीय है। सामान्य मतदाताओं पर अनेक प्रताप्त के दाव हैं। सामान्य मतदाताओं पर अनेक प्रताप्त के दाव हुने हैं । अत सावजिक एवं सुने कप म हाथ उठाकर प्रतादान करने म वह पूर्णत स्वत कहीं सकता। हैरियटन (Harrington) उन कुछ संवप्रचय विचारकों में या जिहान स्वतः प्रवाप्त का समयक किया है। बे प्याप्त भी पुर्त सतदान के लिए गुप्त रीति का समयन किया है। बे प्याप्त भी पुर्त सतदान की समयक या। दीय एवं सम्बंधिया के प्रचात ही मता सं गुप्त मत्त वाल सम्बन्धी विधि पारित हो सकी थी। अब सभी देशों म गुप्त मतदान का त्यार हो। यह स्था की प्रयुक्त मतदान की प्रवस्था मान्यता प्राप्त हो पर्यो है।

बया मतदान अनिवाय होना चाहिए?

इस प्रश्न का उत्तर इस प्रका थे उत्तर पर निमर है कि मताधिकार एक दायित्व है या नाय ? राजनीति सास्त्र के प्राय सभी लेखक यह स्वीकार करते ह वि मताधिकार एक दायित्व है जो राज्य हारा ऐसे सभी व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो उस सम्पादित करने क मोग्य हाते है। यह एक विधिक अधिकार है, न कि प्राकृतिक अधिकार। यदि मतदान सावजनिक हित में एक दायित्य है तो इसका तक

¹² Ibid , p 532

¹³ Mill Representative Government, Ch X

⁴ Trestschke, cited by J W Garner op cit, p 532

सगत निष्कप यह निकलता है कि निर्वाचन का जपन कतव्य को अनिवायत सम्पादित करना चाहिए । प्रस्त यह है कि क्या विधि द्वारा मतदाता की मतदान रूपी दायित्व के सम्पादन के लिए बाध्य किया जा सकता है ? क्या विधि द्वारा अनि-वाय मतदान की व्यवस्था करनी चाहिए? क्या इस कतव्य के सम्पादन म असफल रहने वाले व्यक्तिया वो दण्डित किया जाना चाहिए [?] विभिन्न विचारका एवं राज नीतिनो ने अनिवाय मतदान का समधन किया है । कुछ देशा म तो अनिवाय मतदान की व्यवस्था को अपनाया भी गया था। 1893 ई के देलजियम के सविवात म अनिवास मतदान का विधान था और मतदान न करने पर एक से तीन फ्रेक तक के आर्थिक दण्ड की व्यवस्था थी। चार वार मतदान का प्रयोग न करने पर नागरिक को मताधिकार से विचित कर देने सम्बाधी नियम था। 1907 ई म स्पन म अनि-वाय मतदान प्रारम्भ किया गया या और मतदान न करने पर टव्ड की व्यवस्था थी। गानर के अनुसार स्पन म अनिवाय मतदान सम्बाबी विवि एक मत पत्र मात्र बना रहा नयांकि ग्रामीण निवाचन क्षेत्रों मं 80 प्रतिशत मतदाता निर्दाचना म अनुपरियत रहते थे।1

1912 ई म जर्जें टाइना, 1917 इ म नीदरसैण्ड एव 1950 ई म चको स्लोबाकिया म अनिवाय मतदान व्यवस्था को प्रारम्भ किया गया । फ्रा स म 1875 ई म सीनेट के मतदाताओं के लिए अनिवाय मतदान की व्यवस्था थी। 1921 ई मे प्रो जोसेफ बारथेलिमे (Joseph Bartbelemy) ने फास के निम्न सदन के सदस्य को निर्वाचित करने के लिए जनिवाय मतदान सम्ब वी विधेयक प्रस्तुत किया या लेकिन वह पारितन हो सका।

अनिवाय मतदार का प्राय सभी राजनीतिक विद्वाना तथा राजनीतिनो ने निम्नाक्ति आधार पर विरोध किया है

- (1) राजनीति शास्त्र एव सावजनिक नीति क सृहद सिद्धा ता के आधार पर अनिवाय मतदान का समयन नहीं किया जा सकता।
- (2) अनिवार्य मतदान इस बारणा पर आबारित है कि मताधिकार एक विधिक कतन्य हे जबकि वास्तव म मताधिकार एक विशेषाधिकार और नतिक कतन्य है। अत राज्य यदि नागरिक ना मताधिकार के प्रयोग के लिए बाध्य करता है ता उसके दुरपयोग की अधिन' सम्मावना है।
- (3) गानर का मत है कि अनिवाय मतदान की व्यवस्था के फ्लस्वरूप मता की खरीद करना सरल हो जायेगा । अनिच्छक मतदाताओ को घन के लोग म सरलता से फसलाया जा सकेगा ।
 - (4) जिनवाय मतदान का एक सहज परिणाम यह भी होगा कि मतदाता

¹⁵ Garner op at, p 501

868 | जाधुनिक शासनता प्र

अनुत्तरदायी दग से अपन मत का प्रयोग करेंगे। मतदाता की हिन्दि म किसी उम्मीदवार के उपयुक्त न होने पर यदि वह अपने मत का प्रयोग करता है तो उसके मत 🕅 कोई व्यावहारिक मृत्य नही होता।

वतमान समय म अधिकाश दशा, यया—संयुक्त राज्य अमरिका, क्रनाडा इगलण्ड, स्विट्जरलण्ड, भारत आदि—म अनिवास मतदान व्यवस्था प्रचलित नही है।

निर्वाचन क्षेत्रो का निर्माण

निर्वाचन क्षेत्रा के निर्माण का प्रश्न प्रतिनिधित्व से धनिष्ठ रूप स सम्बर्धित है। प्रतिनिधित्व सं सम्बर्धित दो मुख्य प्रश्न हं (1) प्रतिनिधित्व का उचित आधार क्या होना चाहिए ? (2) प्रतिनिधित्व किसका होना चाहिए ? प्रतिनिधित्व के उचित जाधार के निरिचत हो जाने पर ही निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण निभर करता है। क्षेत्र या प्रदेश, व्यवसाय या पशा तथा समुदाय या सम्प्रदाय प्रतिनिधित्व के विभिन्न एव मा य आधार हैं। इन्हें त्रमश क्षेत्रीय या प्रादेशिक, व्यावसायिक एव साम्प्रदायिक प्रति-निधित्व की सज्ञा दी जाती है। अधिकाश देखा म प्राद्धिक या क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धात माय है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के अत्वयत सारे दश की प्रतिनिधित्व की इप्टि से निर्वाचन क्षेत्र। म विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र स सर्वाधिक मत या बहुमत प्राप्त करन वाले सदस्य को जनता अपने प्रतिनिधि के रूप म निर्वाचित व रती है। इस 'एक निर्वाचन क्षेत्र एव एक सदस्य' का सिद्धान्त भी कहत है। इसके विपरीत, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के अत्तरत विभिन्न व्यवसायी एव धारी म सलग्न व्यक्तियो के पृथक पृथक समुदाय होते हैं और इन व्यावसायिक समुदायो द्वारा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का स्थान ग्रहण किया जाता है। एक व्यवसाय मेसलान सभी व्यक्तियाद्वाराएक याअधिक व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं। अंत व्याव सायिक प्रतिनिधित्व में 'एक निर्वाचन क्षेत्र तया अनेक प्रतिनिधियां' का विचार माय है । प्रादशिक निर्दाचन क्षेत्र एकसदस्यी होत हैं, व्यावसायिक या समानुपातिक प्रतिनि थित्व प्रणाली के अत्तगत बहुसदस्यी निर्वाचन क्षेत्रा का निर्माण किया जाता है। एफसदस्यी (क्षेत्रीय) निर्वाचन-क्षत्र

सम्भूण राज्य म स जितने प्रतिनिधिया को चुनने का निश्चय किया जाता है, उतने निर्वाचन क्षेत्रों में उसे विमाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र म निर्धारित जनसच्या से अधिक व्यक्ति तहीं होते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र से सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला म्वल एक ही प्रतिनिध चुना जाता है। मारत, इनलैंग्ड, समुक्त राज्य भरिका सौवियत क्स, कनाडा, आस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान आदि देशों म क्षेत्रीय अर्थात एमसस्थी निर्वाचन पद्धति प्रचित्त है। इसके गुण निम्मवत है

- (1) यह सुविधाजनक पढ़ित है। इसम निर्वाचन क्षेत्र छोटे होते हैं, फ्लस्वरूप मतदातागण सभी उम्मीदवारो स सरलता स परिचित हो। सकत है।
 - (2) प्रतिनिधि के लिए स्थानीय समस्याओं का अध्ययन नरना सरल हाता

है, निर्वाचन का प्रव घ आसानी से किया जा सकता है तथा मतदाताओं को भी मत देने म सरलता होती है।

(3) निर्वाचन म व्यय भी कम होता है तथा निर्वाचन के पश्चात मतगणना एव परिणामों की पोपणा करना सरल होता है।

(4) इस प्रणाली के जतगत अल्पसस्यक वर्गी एव दलो का भी समुचित प्रति-निधित्व प्राप्त हो जाता है।

(5) इस प्रणासी के अन्तयत दश के सभी क्षेत्रो की विधानमण्डल म प्रति-निष्ठित्व प्राप्त हो जाता है।

एकसदस्यी निर्वाचन प्रणाली के दोव निम्नाकित है

(1) इस प्रणाली के डारा स्थानीयता की मावना म वृद्धि होती है। प्रति
निधिया म सम्पूण देश की अपका एक क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करने की प्रवित्ति
विकसित हो जाती है। व राष्ट्रीय हिंदा की अपेक्षा स्थानीय हिंदो पर अधिक वल दने
कारते है। इस मत का समयन का स्था इटली की एकदलीय प्रणाली के व्यावहारिक
अनुसयी स मी होता है। 18

- (2) निर्वाचन क्षेत्रा की जनसस्या सदब एक समान नहीं रहती, वह धटतीघडती रहती है। अत क्षेत्र को निर्वाचन का आधार मानना ही तृष्टिपूर्ण है। जनसर्या
 म परिवतन होन के कारण निर्वाचन क्षेत्रा के पुन विमाजन की सम्मावना सदैव बनी
 रहती है और पून वर्गीकरण के समय सत्तास्व दल निर्वाचन क्षेत्र का विमाजन हर
 प्रकार करते हैं कि उसे सबसे अधिक लाम प्राप्त हो सके। विरोधी दल के समयका
 को प्रत्यक निर्वाचन क्षेत्र म अब्द-सस्या म कर दिया जाता है। यही मही, विरोधी
 हलों की शक्ति को सीमित करने के उद्देश्य से उसके समयका ने क्षेत्रों को एक या कुछ
 निर्वाचन क्षेत्रों म सीमित कर दिया जाता है, फलस्वस्य विभिन्न आकार के निर्वाचन
 क्षेत्रों का निर्माण हो जाता है। इससे निर्वाचनों म विरोधी दलों को केवल बीडे म
 क्षेत्रों का निर्माण हो जाता है। इससे निर्वाचनों म विरोधी हलों को केवल बीडे म
 सोने ही एकलता प्राप्त हो पाती है। इस त्रया को ग्रेशीन क्षेत्र (Gertymander
 18) कहते है। इसका प्रयाग सवस्यम 1812 ह मे समुक्त राज्य अमेरिका म
 सर्वाच्युतेट्स राज्य के राज्यवात ऐत्तिक भरी किया था।
- (3) कभी कभी किसी निर्वाचन क्षेत्र भ योग्य उम्मीदवारा के अनाथ में मत-दाता साधारण न्यक्ति को या निर्वाचन क्षेत्र के बाहर के किसी योग्य न्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनत हैं। इस दोष की सम्मादना केवल उन निर्वाचन धेरो म ही होती है जहां स्थायी निवास सम्बन्धी योग्यता निर्घारित नहीं की जाती। अमेरिका म निर्वाचन क्षेत्र में स्थायी निवास सम्बन्धी अनिवाय योग्यता का विभान है। इसके विपरीत भारत म किसी निवाचन क्षेत्र से कोई भी नागरिक निर्वाचनसम्बन्धी योग्यताश कं पूण

¹⁶ Garner, cited by A Appadoras The Substance of Politics p 475

होने पर चुनाव तड संस्ता है। निर्वाचन क्षेत्र म[्]निवास सम्ब धी काई याम्यता मारत म निर्धारित नहीं की गयी है।

(4) धेत्रीय पद्धति के अधीन कुल निवाचका व अल्प मत का ही प्रतिनिधित्व करम वाल व्यक्ति निर्वाचित्रहो जात हैं। बारत एव ब्रिटेन के ससदीम निवाचना ने ऑकटे इस मत की पुष्टि करते हैं। भे असफल उम्मीदवारा को जा मत प्राप्त हात है व व्यथ चले जाते हैं और उन्हें भोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हाता है। मसब या विधानमण्डल म विधिन्न दसा का निर्वाचना में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है। मसब या विधानमण्डल म विधिन्न दसा का निर्वाचना में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है। सेत जब निर्वाचन म विकाशास्त्र क्षय होता है तो सफल उम्मीय वार सो निष्यय हो कुल सवदाताना का स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, वह अल्पमत के समयन से ही विजयो हो जाता है। अत इस पद्धति का एक दुष्पिणाम यह होता है कि अल्पमत विधानमण्डल में प्रतिनिधित्व से विजत हो जाता है। इस पद्धित के आलोचका द्वारा समानुषातिक प्रतिनिधित्व से विजत हो जाता है। इस पद्धित के आलोचका द्वारा समानुषातिक प्रतिनिधित्व स्थानिक स्थित हो जाता है।

(5) एक्सदस्यो निर्वाचन-क्षेत्र बहुसदस्यो निर्वाचन क्षेत्र। की अपेक्षा छाटे होते हैं। अत शासक वग निर्वाचना को नियम्त्रित करने म सफल होता है। इन दोपा के कारण हो 1918 के म फास ने एकसदस्यी निर्वाचन प्रणाली का परित्याग कर

दिया था।

बहुसदस्यो निर्वाचन क्षेत्र प्रणासी

बहुसदस्यी निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली सामा य टिकट प्रणाली (General Ticket System) ना सशोधित रूप है। 'सामा य टिकट प्रणाली' के अतगत सम्पूण देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है और मवदाताओं द्वारा सभी घरस्या के निर्वाचना में माग लिया जाता है। प्रस्थक मवदाताओं वर्तने सत प्राप्त होते हैं जितन स्वामा में निर्वाचना के निर्वाचना के निर्वाचना के निर्वाचना के निर्वाचन के निर्वचन के निर्वाचन के निर्वचन के निर्वचचन के निर्वचचन के निर्वचन के निर्वचन के निर्वचन के निर्वचचन के निर

^{17 1924} ई के ब्रिटिश निवाचना म अनुदार दस का केवस 48% मत प्राप्त होन पर भी 615 स्थानों म से 412 स्थान प्राप्त हुए वे, अम दस की 25% मत पर दें और अवर्धात 151 स्थान और विदार दस को 20% मत पर पु केवस 8% अर्थात् 46 स्थान प्राप्त हुए थे। 1951-52 ई के प्रथम मारतीय निर्वा चनों में कांग्रेस दस को 44 85% मत प्राप्त हुए पर तु वोकसमा म 489 स्थानों में अर्थे दस्यान प्राप्त हुए थे। इसी निवाचन में समाजवादी दस को 10 5% मत प्राप्त हुए पर तु वोकसमा म 450 स्थानों में अर्थे सा उसे केवस 12 स्थान प्राप्त हुए पर तु वोकसमा में 50 स्थाना की अर्थे सा उसे केवस 12 स्थान प्राप्त हुए थे। 1957 ई के निर्वाचना में कांग्रेस को 47 8% मत और वोकसमा में 75 1% स्थान, 1962 ई में वालेस को 44 5% मत और 72 8% स्थान, 1967 ई म 40 7% मत और 53 5% स्थान प्राप्त हुए थे। वेसिस मान 1967 ई म 40 7% मत बोर 53 5% स्थान प्राप्त हुए थे। वेसिस मान 1967 ई म 40 7% मत बोर 53 5% स्थान प्राप्त हुए थे। वेसिस मान समीक्षा, जब 4, अर्थेन जन 1972, प्र 36

के लिए 'सामा य टिकट प्रणाली' ही प्रचलित थी। लेकिन आधुनिक विद्याल राज्या के लिए यह प्रणाली अव्यावहारिक है। अल्पसस्यको को इस पद्धित के अतगत प्रति निधित्व प्राप्त होने की कोई आधा नहीं रहती। बहुसस्यक मत पाने वाले दल के प्रत्यादी ही विजयी होते ह फलस्वरप घेप दला की प्राप्त मतः व्यथ चले जाते ह। यह निर्वाचन प्रणाली कठोर एव जटिल है। प्रतिनिधियों का मतदाताजा से सीधा सम्यक नहीं होता है और प्रतिनिधि यो अपने क्षेत्र की समस्याओं का उचित प्रतिनिधित करने य असफल रहते हैं।

बहुसदस्यी निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली एकस्वस्यी एव सामाप्य टिकट प्रणाली के मध्य का माग है। इसके अतगत सारे देश की वह निर्वाचन क्षेत्रा म विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र इतना विस्तृत होता है कि दो या अधिक सदस्या को उस निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि रूप मे चुना या सके। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अतगत निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यी होते हैं। बीमर प्रणाली 1919 33), क्षा के अतगत निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यी होते हैं। बीमर प्रणाली प्रवित्त है। भारत में एकसदस्यी एवं बहुसदस्यी दोना ही प्रकार के निर्वाचन क्षेत्र पाये जाते है। भारत में एकसदस्यी एवं बहुसदस्यी दोना ही प्रकार के निर्वाचन क्षेत्र पाये जाते है। बहुसदस्यी निर्वाचन क्षेत्र पाये जाते है। बहुसदस्यी निर्वाचन क्षेत्र पाये जाते है। वहसदस्यी निर्वाचन क्षेत्र एवं क्ष्य मतदाताओं के सभी वर्षों एवं अस्पसद्यका की उचित प्रतिनिधित्व देना है।

इन दोनो प्रणालिया म 'एकसदस्यी निर्वाचन क्षेत्र' प्रणाली अधिक अध्ठ है और प्रचलित भी है। इसका सबसे वडा गुण यह है कि इसके अधीन इट एव स्थायी सरकार का निर्माण सम्मव होता है। इसके विपरीत, बहुसदस्यी निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तायत देश म छोट-छोट राजनीतिक दला का उट्ट हो जाता है और किसी भी दल को विधानमञ्जल म स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता। फलस्वक्य सस्वीय कायालीक स्थाया रूप में हहतापूर्वक काय नहीं कर पाती है। अधिकाश्यत बहुसदस्यी निर्वाचन क्षेत्रीय प्रणाली के अधीन समुक्त मित्रमण्डला का निर्माण होता है। फार उत्सम प्रमुख उदाहरूण है। इसके ही कारण कार का चतुन्य गणत श्रीय सविधान असकल रहा था और पत्रम गणत तीय सविधान का निर्माण अनिवाय हो एया था।

अल्पसटयको को प्रतिनिधित्व

प्राय हर देश म विभिन्न प्रकार के अल्यसस्यक पाय जात है। इनके प्रति-नियित्व का प्रका राजनीति शास्त्र की एक महत्वपूष समस्या है। क्षेत्रीय निवाचन प्रणाती के अपीन अल्यसस्यका की जयनी जनसस्या के अनुसार प्रतिनियत्व प्राप्त नहीं होता और निवाचनो म बहुत बढ़ी सख्या म मत स्थय चले जात हैं। विधान (Legislatian) के सम्बाध म सम्मूण जनता नो निषय और विचार विभन्न करने ना अधिकार देवेत प्र काएक माग्य सिद्धात है। अत विधानसम्बत्ता म अल्यस्यका का प्रतिनिधित्व एव उनक प्रतिनिधित्वा के विचारों का सुना जाना लोकत प्रमा अधिकाधिक पावन सम्मव है। अत यह आवस्यक है कि अल्पसस्यका को विचार विमय क उचित अवसर प्राप्त होन चाहिए। साथ ही साथ उनकी उचित इच्छाओं का मा यता भी प्राप्त होनी चाहिए। जहाँ अल्प सस्यका भी उपसा की जाती है वहाँ उनम अस तीप एव आक्रीश उत्पन्त हो जाता है। अल्पसस्यका को प्रतिनिधित्व देने एव क्षेत्रीय निर्वाचन प्रणाली क दायों को दूर करते के लिए प्रस्तावित विधिन न निर्वाचन सम्बन्धी उपाया म समानुपातिक प्रतिनिध्त्व देला प्रसावित क्षेत्र में लिए प्रस्तावित विधिन न निर्वाचन सम्बन्धी उपाया म समानुपातिक प्रतिनिध्त्व प्रणाली का प्रमुख स्थान है।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली

इस प्रणाली का सुभाव सवप्रथम 1851 ई म इपलब्ह क एक निवासी पामस हेयर (Thomas Hare) न अपनी पुस्तक 'निवांचन एव प्रतिनिधित्व' (Election and Representation) में दिया था। यह निवांचन पद्धति समानुपातिक प्रति-निधित्व प्रणाली के नाम स विख्यात है। इसके दो रूप ह (1) एकल सक्रमणीय प्रणाली (Single Transferable Vote System), एव (2) सूची प्रणाली (List System)

(1) एकल सकमणीय प्रणाली —हैयर प्रणाली को एकल सकमणीय मत प्रणाली की भी सना दी जाती है। यह इस सिद्धात पर आधारित है कि सच्चे लोकत त्रीय देशों के विधानमण्डला म देश के विभिन्न वर्गों को जनसच्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए।

एकत सक्रमणीय मत-प्रणाली की कुछ भौतिक विशेषताएँ है, जो निम्ना-कित हैं

(1) इस प्रणाली के अन्तमत निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यी होते हैं अर्थात् एक निर्वाचन क्षेत्र स कम स कम तीन सदस्य तो निर्वाचित होन ही चाहिए।

- (2) प्रत्यक मतदाता को केवल एक मत प्राप्त होता है पर तु निवाबन क्षेत्र से चूने जाने वाले प्रतिनिधियों की सख्या के वरावर अपनी पस दगी व्यक्त करने का अधिकार होता है। अत मतदाता का मत तो एक ही होता है पर तु उसके प्रयोग के सम्बन्ध म वह अपनी पत्त दगी (preference) व्यक्त कर सकता है। उदाहरणान, किसी निर्वाबन क्षेत्र से तीन सदस्य चुन जाने है लेकिन 6 व्यक्ति चुनाव लड रह है तो ऐसी स्थित मं मतदाता को इन 6 उम्मीदवारों म से अपनी पस द के उम्मीदवारों में समया प्रयान, दितीय एव ततीय पत्त दगी को व्यक्त करने का अधिकार होता है। यदि प्रयान पत्त दगी पाने वाला व्यक्ति विजयीं नहीं होता तो मतदाता का मत व्यव नहीं जाता, वह द्वितीय एव यदि आवस्यनता हुई तो तृतीय पत्त दगी के रूप म इस्ता तिस्त
- (transfer) हो जाता है।

 (3) इस प्रणालो न अन्तगत निवाचित होने के लिए एक निश्चित सरया
 व्यक्ति मता के निर्धारित कोटा ने बराबर मत प्राप्त करना आवश्यक होता है। इस
 नोटा को निर्धारित करन नी रीति अग्राणित है

हाले गयं मता की वुल रख्या निर्वाचित हान वाल सदस्या की सहया +1

अर्थात निर्वाचन म डाले गय जुंन मता की सस्या म निर्वाचित होने वाले सदस्या की सम्या म 1 को जोडकर उसका मान दे दिया बाता है और जो माज्यफत जाता है वहीं काटा होता है। जुष (Droop) ने इसम घोडा सद्योधन कर दिया है। उहाने कोटा तिपारित करने के लिए माज्यफल म 1 नी सस्या को और जोड दिया है। उदाहरण के लिए, 'ले निर्वाचन क्षेत्र स 3 प्रतिनिधि चुन जाने हं और निर्वाचन मुक्त 8 000 मतदातावा न मतदान किया है। इस स्थित मे हेयर तथा एण्डे के अनुसार निर्वाचित होन के लिए 2000 मता का निर्धारित कोटा है परातु हुए के अनुसार 2,001 मत निर्धारित कोटा है परातु हुए के अनुसार 2,001 मत निर्धारित कोटा हो गाजकर मा यहै।

(4) यदि किसी उम्मीदवार को कोटा संअधिक मृत प्राप्त होते हैं तो निर्धारित कोटा से प्राप्त अधिक मृतो को उनकी दितीय एवं उसके वृहवात तृतीय पसंदगी के अनुसार अय उम्मीदवारों में वितरित कर दिया जाता है।

मताणना के समय सवप्रयम प्रयम पस दशी के मंता की गणना कर ली जाती हूं। जिस उम्मीदवार को प्रयम गणना म निर्धारित कीटा के बरावर मत प्राप्त हो जाते हैं वह विजयी घोषित कर दिया जाता है। यदि प्रयम मतगणना म ही प्रयम सदाण तो स्वर्ध के आघार पर निर्धार्थ के से चुने जाने वाले सभी उम्मीदवारों को निर्धार्थ के आघार पर निर्धार्थ के से चुने जाने वाले सभी उम्मीदवारों को निर्धार्थ के आघार पर निर्धार्थ के खाता है। यर तु यह भी सम्मव है कि प्रथम मतगणना म समी सवस्य न चुन जायें। ऐसी स्थित म सफल उम्मीदवारों के अविरिक्त मता को उनकी दितीय पर स्था के अनुसार वितरित कर दिया जाता है तथा पुन मतगणना होती है। यह कम उस समय तक चलता रहता है जब तक कि सभी सवस्य का चुनाव नहीं कर लिया जाता। यदि फिर भी काई स्थान रिक्त रह जाता है या प्रथम मतगणना म कोई उम्मीदवार निर्धारित कोटा के बराबर मत प्राप्त नहीं करता है तो सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मता को रह करके उहे शेप उम्मीदवार निर्धारित कर दिया जाता है। सामा यत नीचे की तरफ से मता का हस्ता वर्ण जनर की अवसा सतगणना प्रक्रिया के व तम हो किया जाता है।

(2) सूची प्रणासी—समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणासी का यह एक दूसरा तरीका है। इस प्रणासी के अ तगत भी बहुसदस्यी निर्वाचन क्षेत्र होते है, प्रत्येक मतदाता की उतन ही मत प्राप्त होते हैं जितने कि उस निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य चुने जाने है। किसी मतदाता इरा निर्मा एक व्यक्ति को एक से अधिक मत नहीं दिया जा सकता। इस प्रणासी में एकस सक्रमणीय पदित की तत्तर हो निर्माचन कोटा निर्मादित किया जाता हैं, परातु उम्मीदबारा की उनके दक्षीय आधार पर सूचिया तैयार की जाती हैं। निर्माचन एक दल को प्राप्त कुल मतो के अनुसात म उस दल के उम्मीदबार चुने

है। दल की सूची म स सबस अधिक मत पान बास उम्मीदवारों को अमानुसार चुन लिया जाता है। जमनी ने बीमर संविधान ने अत्तगत इस प्रणाली का प्रयोग निया गया था।

समानुपातिक प्रणाली के पक्ष में तक-यह प्रणाली अय प्रणालिया की अपक्षा समाज के विभिन्न वर्गों एवं समुहा को उनकी जनसंख्या क अनुपात म उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने म मफल होती है। अत यह प्रतिनिधित्व की याययुक्त पद्धति है । किसी का मत व्यथ नही जाता है । विधानमण्डल म किसी दल का इतना निरकुत बहुमत भी प्राप्त नहीं होता कि वह अल्पमत की उपक्षा कर सक । बहुमत वी निरकुशता के विरुद्ध यह पद्धति एक सरल अवरोध है। विधानमण्डल सच्चे जयाँ म लोकत न के अनुरूप देश का दपण होता है। जनता म राजनीतिक चेतना जागत होतो है और किसी मतदाता का मत व्यथनही जाता है। सभी यह जानते हैं कि उनके यत का व्यावहारिक मूल्य है। निर्वाचन क्षेत्र के समस्त दोयो ना इस प्रणाली द्वारा परिहार हो जाता है और 'भैरीम डरिम' जसे दौषा की कोई सम्मावना नहीं रहती। इस प्रणाली के अ तगत सभी राजनीतिक दला को देश के राजनीतिक जीवन म काय करने के अवसर प्राप्त हो जाते हैं। यह पढ़ित राजनीतिक त्राचनात्रिक जावन न काव र त क कवतर आपता है। यह दूर होत राजनात्रिक सत्ता की समान रूप से विमाजित करने को एक प्रत्यापूर्ति है। जॉन स्टुअट मिन एव रमने म्योर इसके प्रमुख समधक हैं। मिल के अनुतार इस प्रणाली द्वारा निर्वा का एव निर्याचिता में निकट एव सुट्टड सम्ब थ स्थापित हो जाते है क्योंकि हर प्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्र म जन-सम्मिति से ही चुना जाता है। 18 इसके अतिरिक्त समानुपातिक प्रतिनिधित्व पर बाधारित विधानमण्डल का वौद्धिक एव नतिक स्तर भी ऊँचा हो जाता है। बुद्धिजीविया को सफलता की सम्भावना उह निर्वाचना म माग क्षेत्र के लिए प्रेरित करती है। इसके अतिरिक्त बहुमत दल भी निर्वाचन म अपन उम्मीदबारा का सोच समभकर खंडा करता है। वे चरित्रवान एव बुद्धिमान उम्मीद-बारों को मनोनीत करने के लिए बाध्य होते हैं। निदलीय एवं स्वतं न जम्मीदबार भी इस पद्धति के अभीन निर्वाचित हो जात हैं। लॉड एक्टन (Lord Acton) में समानुपातिक पद्धति का समयन किया है। उनके अनुसार यह पद्धति अस्पिधक लोक-तात्रीय है और हजारा एंसे व्यक्तियों के प्रसाव का सम्भव बनाती है जिनकी शासन म इस पद्धति के जमाव में कोई शावाज न होती । इस प्रणाली म कोई मत व्यथ नही जाता है । हैलेट (Hallet) समानुपातिक प्रतिनिधित्व को लोकतान की कुजी मानता है। ए बी कीय ने ब्रिटिश मित्रमण्डलीय प्रणाली के सम्बन्ध म समानुपातिक पद्धति वा समयन करते हुए उसके चार गुणो का उल्लेख किया है

(1) इस पद्धति के अत्तगत काँम स समा म निर्वाचना म विभिन्न दला की शक्ति मे अनुपात म सदस्य चुने जायेंगे।

18 Mill On Liberty etc pp 256 257

- (2) एक्सदस्यी निर्वाचन क्षेत्र की अपक्षा मतदाताओं को उम्मीदवारा के चयन म अपक्षाकृत अधिक स्वतानता प्राप्त होगी।
- (3) मतदाता स्वत व एव चरित्रवान लोगा को सरलता सं चुनन म सफल हा सकेंगे !
- (4) निदसीय मतदाताआ का प्रमाय प्राय घू य हो जायगा। 19 रैमजे म्योर क अनुसार एकसदस्यीय निवाचन क्षेत्र के दोषा को समानुपाति र प्रतिनिधित्व की प्रणाली से ही दूर करना सम्भव है। 9 म्योर ने भी जिटन में एकल-सन्मणीय मत प्रणाली को अपनाने का सु-भाव दिया था। उसका मत था कि इसके अत्यात वतमान पद्धति ही अपक्षा होंग स समा म राष्ट्र का अधिक उचित प्रतिनिधित्व सम्भव होगा। मतदाताआ को विभिन्न उम्मोदवारा म से अपने प्रतिनिधि को चुनने की वास्तिवक स्वताता प्राप्त होगी। यह पद्धति मतदान में अनुवित एव अष्ट तरीकां के प्रयोग को हत्तीसाहित करती ह। मतदाता अपने अात हरण के अनुसार मतदान करने क लिए स्वतात्र होते हैं। इस पद्धति म वतमान प्रणाती के सयोग के तत्व के लिए कोई स्थान नग्नी होता है। 21

समानुपातिक प्रणालों के विरोध में सक-समानुपातिक पदिति के उपरोक्त गुणा के होते हुए उसके विरोधियों नं उसकी तीय बालोचना की है । इस पदिति के प्रमुख दोप निम्नलिखित हं ²

- (1) यह पद्धात अत्यधिक जटिल है एव उसकी प्रत्रिया कठोर है और सामा य मतदाता की समभ के बाहर है। जिन देशा की यहुतस्थक जनता अशिक्षित है, वहा तो इसकी असफलता निश्चित है। मतगणना के लिए भी विद्येप योग्यता की आवश्य कता हाती है। इसके अतिरिक्त मतगणना म अनुचित साधना के प्रयोग की भी सम्मा बना होती है।
- (2) इसक अ तमत निवाचन क्षेत्र बहुत बड़े या विस्तृत होते है । अत सदस्या और मतदाताआ म प्रत्यक्ष एव निकट के सम्पक्ष की कोई आझा मही होती ।
- (3) तिजविक के अनुसार यह पद्धित ससदीय श्रष्टाचार की वृद्धि म सहायक होती है। विधि निर्माण म अमेरिका म प्रचलित लॉगरोलिंग (Logrolling) एव पोक वैरल (Pork Bereel) जसी बुराइया उत्पन्न हो जाती हैं तथा राष्ट्रीय हित की अपेक्षा वर्गीय हित की ट्रिंट से विधिया ना निर्माण किया जाता है।
 - (4) इस पद्धति का सबसे वडा दोप यह है कि देश म छोटे छोट दलो एव

¹⁹ Keith The British Cabinet System, pp 335 336

²⁰ Ramsay Muir How Britain is Governed, 1951, pp 134 35

²¹ Ibid, pp 139 40

²² Ramsay Muir op cit, pp 140 143

सगठनो अर्थात बहुदलीय पद्धति का विकास होने लगता है और राजनीतिक अस्थिरता के लिए माग प्रशस्त हो जाता है। देश म गुटव दी की महामारी फल जाती है। विधानमण्डल मे अनक दलो के होने के कारण ससदीय जासन स्थिरता एव सफलता पूरक नहीं चल पाता । बहुदलीय पढित के ज तगत संयुक्त या मिश्रित में निमण्डला के ... निर्माण होते है तथा राजनीतिक सौदेवाजी एव भ्रष्टाचार के लिए माग खुल जाता है। छोटे छोटे विभिन्न दल अपने हिता की हिष्ट सं सोचने सगते हैं। अन्यसंख्यकों के सगठन अपने वर्गीय स्वार्था की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहते है। विधानमण्डल परस्पर विरोधी विचारा एव हितो का अखाडा वन जाता है। फ्रांस इसका उदाहरण है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में उप निर्वाचन सम्भव नहीं है क्योंकि इस हेतु एकसदस्यी निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण करना आवश्यक होता है। यदि यह असम्भव नहीं तो कठिन अवस्य ह एवं इससे सम्बर्धित अनेक प्रश्न उठ खडे होत है।

सिजविक, डायसी, लास्की एव फाइनर इस पद्धति क तीव आलोचक थे। डायसी का मत था कि समानुपातिक प्रणाली म दला का प्रमाव बहुत वढ जाता है और मतदाताओं को नाममान की स्वत नता प्राप्त होती है। डायसी की यह भी मा पता थी कि जितनी अधिक जटिल निर्वाचन-पद्धतिहोसी, मतदावा परजतनाही अधिक राजनीतिक दलो का प्रमाव भी होगा। त्रो आस्की व समानुपातिक पद्धति के सम्बन्ध म रमजे म्योर के विचारों संसहमत नहीं है। रमजे म्योर के सकी को सबल एव प्रमावशाली मानते हुए भी व समानुपातिक पढित को पूणत त्रुटिपूण मानते हैं। लास्की के अनुसार "इस बात का काई प्रमाण नही है कि फास में जहाँ समूह प्रणाली प्रचलित है, विधानमण्डल की स्थिति हमारे यहा स थेष्ठ है। 'रमजे म्योर ने ससद का राष्ट्रीय विचारा का दपण बनाने हेतु समानुपातिक पद्धति की वाखनीयता का उत्लेख किया है। यदि स्योर के इन विचारों को मान भी लिया जाय तो स्यार द्वारा सम यित दलीय पद्धति क अ'तगत भी समानुपातिक प्रणाली क अधीन किसी दल का स्पष्ट बहमत प्राप्त नहीं हो सकता और कोई दल बिना अपन विपक्षी क सहयोग के स्यायी मित्रमण्डल या शासन नही बना सनेगा। द्वितीय, बहुदलीय पद्धति क फलस्वरूप मिश्रित या अल्पसत्यक मा त्रमण्डला के ही निर्माण सम्मव हैं। अल्पसत्यक द्वासन के दोषा पर प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है । इसमें नीति का स्थान पड्यान ले लेता है। मित्रमण्डल की सहायता करन वाला दल एक प्रकार स स्वामी क रूप म आचरण करता है। शासन के द्वारा जाय दला का सहयोग अजित करने के लिए सिद्धाता का परित्याग कर दिया जाता है। अत उसक कार्यों म सदव साहस एव सगति का अनाव रहता है। व उमलैण्ड व सादभ म समानपातिक प्रतिनिधित्व की अवाधनीयता की

²³ Laski Parliamentary Government in England, op cit, p 77

²⁴ Laski Ibid , p 78

चचा करते हुए लास्की ने कहा है कि बहुदलीय व्यवस्था या समानुपातिक प्रतिनिधित्व के फलस्वरूप मित्रमण्डलीय एव दलीय निय नण नष्ट हो जाता है जिसके फलस्वरूप शासन काय बहुत कम सातोषजनक होता है। 5 समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या मित्रमण्डल तथा काँम स समा के सम्ब थो म परिवतन करके यदि काँम स समा के सुधार का प्रयत्न किया जाता ह तो लास्की के अनुसार यह प्रयत्न महामारी को साधा-रण औपधि से ठीक करन के समान ही है। समानुपातिक प्रतिनिधिस्व प्रणाली से जमनी की रक्षा नहीं हो सकी थी और फार्स में निदलीय सदस्यों में क्याप्त अपने विचारा के अनुसार शासन को अपदस्य करने की प्रवत्ति बहुत कुछ वैसी ही है जिसका हम सामना कर रह है।' ⁶ लास्की की यह मा यता थी कि समाज म सामा यत तीन विचारधाराएँ होती ह (1) वे जो सामाजिक व्यवस्था म कोई विशय परिवतन नही चाहते, (2) जो समाजवादी विचारचारा के आधार पर परिवतन के पक्षपाती होते है, एव (3) जी पूरी तरह व्यक्तिवादी पूजीवादी व्यवस्था के पक्षघर होते है। अपरिवतनवादी एव व्यक्तिवादी एक ही श्रेणी मे रखेजा सकते है। अत व्यवहार म समाज म केवल दी अर्थात् व्यक्तिवादी एव समाजवादी विचारधाराएँ ही होती हं। अत लास्की, रेमजे म्योर द्वारा प्रतिपादित जिदलीय—दक्षिणपथी, वामपथी एव के द्वीय—धारणा को जन मत की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं मानता । उसके अनुसार उपरोक्त दो विचार-धाराजा के जाधार पर ससदीय व्यवस्था म द्विदलीय पद्धति ही शासन के स्थापित एव उनिति के लिए आवश्यक है।

फाइनर ⁷ न समानुपातिक प्रतिनिधित्व की आसोचना करत हुए कहा है कि यद्यपि यह पदित गणितीय ह्रांट्ट स समान प्रतिनिधित्व प्रदान करन म असफल होती ह पर सु इसके अन्तरात मतदाता-मा एव प्रतिनिधित्व प्रदान करन म असफल होती ह पर सु इसके अन्तरात मतदाता-मा एव प्रतिनिधित्वा म घनिष्ठ सम्बध्ध नहीं हो। पात है। इसके अतिरिक्त घासन की स्थितत करके स्थत में शुप्त समूहा के निर्माण का बढ़ावा देती है। ''लमानुपातिक प्रतिनिधित्व निस्स वेह सफल समूहवाद की बिंद के लिए उत्तरदायी होता है।' जमनी में बीमर सिवधान (1919 ई) के अधीन समानुपातिक प्रतिनिधित्व की पदित को अपनाया गया था। 1918 ई म जमनी म केवल 7 वढ़े दल थे। 932 ई में इनकी सख्या 20 के करीब ह्या पायी थी और दलीय विधन्द न से यह प्रवित्त विद्यान एव हित विमिन्न दना पर नियान ज करने सहस्ता स सफल हो जात थे। दलीय परि-पद्या हारा तैयार की गयो लम्बी मूनी म से निर्वाचन क्षेत्रा क उम्मीदवारा का चयन करना सुची प्रणाली की एक मुल्य कठिनाई है।

²⁵ Lasks op est p 218

²⁶ Ibid, p 220 27 Finer The Theory & Practice of Modern Government, op all, p 554

समानुपातिक प्रतिनिधित्य क विरुद्ध लगाय गय उपरोक्त सभी आरोपा का उत्तर उसके समयका रमजे स्थोर, कीय तथा हस्केंज न दिया है। उनके द्वारा इन आरोपा को स्वीकार नहीं विया जाता है कि यह प्रणाली जटिल और असुविधाजनक है । उनके अनुसार इन तकों म भी कोई सार नहीं है कि प्रतिनिधित्व पद्धति में निर्वाचको एव निर्वाचिता म कोई सम्बाध नहीं रहता है और निर्वाचन काम म बद्धि हो जाती है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का फास, इटली, वीमर जमनी तथा आस्ट्रेलिया में प्रयोग किया गया है। ग्रेट ब्रिटेन म इगलग्ड क चन्न की राप्टीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, स्कॉटलण्ड म शिक्षा अधिकारियो का चयन, उत्तरी आयरलण्ड की ससद के दोनो सदनो, आयर के निम्न सदन तथा दक्षिणी अमरिका में सीनेट एवं कुछ नगर-पालिकाओं के निर्वाचन, बनाडा म बुछ नगरपालिकाओं के निर्वाचना तथा भारत म राष्ट्रपति के निर्वाचन " म इस पढ़ित का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त राज्य म समानुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रचलन नगर निर्वाचना तक ही सीमित रहा है। "भारत म 1956 ई के पूर्व माग 'व' एव 'ख' राज्या क राज्यसभा के प्रतिनिधि समानुपातिक प्रतिनिधित्य एव एकल सनमणीय मतानुसार चुन जात थ । बेलजियम, चकोस्लो-वाकिया, फिनलण्ड, जमनी (बीमर सविवान), बिटेविया लियोनिया, पोलैण्ड एव यूगो-स्लाविया म कभी सची प्रणाली का प्रचलन था। 30 सोवियत रूस म समानुपातिक प्रतिनिवित्व का प्रचलन नही है।

फा'स मे समानुपातिक प्रतिनिधित्व

फा'स के चतुष गणतानीय सविधान म समानुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रचलन या। एकसदस्यी निवाचन-क्षेत्रा एव ब्रितीय भववान प्रणासी को कायम रखते के पक्ष म कोई इल नहीं या। सभी ने नायपूण निवांचनी रचन दिया या। वसे तो सभी दल समानुपातिक प्रतिनिधित्व की और उसके गुणा के कारण आकर्षित थे, पर तु सान्य-बादी दल इस पदिति ना विनोय रूप से पर्यापती या यहा तक कि वे एक ही राष्ट्रीय सूची के निर्माण के पक्ष मे थे। उन्होंने एम आर पी (MRP) के इस मुक्सव का

²⁸ Article 55(3) । को महावेचप्रसाद मार्गो क अनुसार भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व का सही प्रयोग नही है। यह तो पस दगी के अनुसार या वैकल्पिक मत्तवान प्रपाती (Preferential or Alternative Vote System) है। — The Government of the Indian Republic, 1972, pp 129-130 । का जीनम्स के मतानुसार अनुच्छेद 55(3) की भाषा दोषपूण है। इसमे उल्लियित पद्धित समानुपातिक पद्धित नही है, हमें एकल सम्मणीय मत कहा जाना चाहिए। — Cited by Dr Asırvatham op cit, p 421
29 Strong Modern Political Constitutions, op cit (1963), p 186

³⁰ A J Zurcher, cited by A Appadorar The Substance of Politics, 9th edn., 1961 p. 478

वृद्धतापूषक विरोध किया कि मतदाताक्षा को उन उम्मीदवारों के नाम जो सूची में नहीं हा, स्वत जिस्तने का अधिकार होना चाहिए। अक्टूबर 1946 ई की विधि के अतगत प्रतेक डिपाटमेक्ट्र को निविचन क्षेत्र मोवित किया गया था, पर तु 6 वडे डिपाटमेक्ट्र को सुचि मत्त्र विधि के अतगत प्रतेक डिपाटमेक्ट्र को सुचि मत्त्र किया गया था। हर निर्वाचन क्षेत्र म प्रविचान सुच मा गया था। हर निर्वाचन क्षेत्र म प्रत्येक दल अपने उम्मीदवारों की सूची प्रस्तुत करता था। कोई सूची पूण नहीं होती थी। मतदाताबा को उसमे नाम सिखन का अधिकार नहीं दिया गया था, मतपत्र म उम्मीदवारों के नाम दलीय पस दगी के अनुसार लिखे जाते थे, मतदाताओं हारा मतप्त पर अपनी पस दगी व्यक्त की जाती थी, मतदाता के अधार पर प्रत्येक स्त्रीय मूची की स्वरूप के अवदान कर सकता था। प्राप्त मता के अनुपात के अधार पर प्रत्येक स्त्रीय मूची की स द्यस्य-सर्था प्रदान की जाती थी और सूची में के व्यक्त नामों या पस दगी के अधार पर सहस्यों मूचन कर सिक्ष जाता था।

भा स म मुद्द दलीय संगठन एवं दलीय मिक के अभाव क कारण इस पदित की अपनाया गया था। एक सदस्यों निवासन क्षेत्र के दीप द्वितीय सतदान प्रणाली के कारण और अधिक बढ़ गय थे। काइनर के अनुसार भारत म समानुपातिक प्रतिनिधिषत को अपनाने का सुरय कारण बहुद लीय पदित थी, परातु इसका प्रभाव उत्तर द्विता । दलों की सरया म और अधिक बृद्धि हा यथी। समानुपातिक प्रति निथित को अपनाने का समयन सबसे अधिक तत्यरता से क्षेत्र साम्यवादी दल ने किया था। इसका एक मुद्य कारण यह था कि दल का अपना ससदीय सदस्यों पर निवित्त एवं पण मिस नण था।

अल्पसस्यक प्रतिनिधित्व सम्ब धी अव्य निर्वाचन प्रवृतियाँ

अल्पसस्यको को उनित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए निम्न पद्धतिया का और प्रयोग किया जाता है

(1) सीमित मत प्रणाली (Limited Vote System)—इस प्रणाली के ज'त्राव बहुसदस्यी निशांचन क्षेत्र होते हुं और क्षत्र स कम तीन सदस्यो का चुना जाना कावस्यक होता है। निर्वांचन क्षेत्र के सदस्यों की सरया से एक कम मत प्रत्येक मत-दाता की प्राप्त होता है अधात् यदि किसी निर्वांचन क्षेत्र से 5 सदस्य चुने जाने हु तो प्रत्येक मतदाता को 4 मत प्राप्त होते हैं। इस प्रणाली म मतदाता हारा एक ही उम्मीदवार को अपन सभी पत नहीं दिये जा सकते हु। वह एक उम्मीदवार को केवल एक ही मत दे सकता है। मतदाता को सदस्या को सरया से कम सदस्या को मत देन का अधिकार होता है अत इसे धीमित मतदान प्रणाली कहते हैं। इस ब्यवस्या में किसी दल में लिए सभी स्थानो पर अधिकार करना सम्मय नहीं होता कम से कम एक

³¹ फास के प्रशासनिक क्षेत्र जस कि भारत म जिलाया कमिक्तरी।

³² Finer op est p 559

880 | आधुनिक शासनतात्र

स्यान तो अस्पसरयका को प्राप्त हो ही सकता है। यह प्रणाली पुतनाल एव समुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्या म प्रचलित है। इस प्रणाली का भी यह दोप है कि अस्पसस्यको को अपन अनुपात म प्रतिनिधित्व प्राप्त नही हो पाता है। इसके अति रिक्त इस पद्धति के अचगत निवाचन क्षेत्र म अस्पसर्यक मतदातामा की सहया भी इतनी कम नहीं होनी चहिए कि वे प्रमावी सिद्ध न हो सर्के।

- (2) सामृहिक मत प्रणाली (Cumulative Vote System)—इस पढिंत मं में बहुयदस्यी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं । मतदाता को उतन ही मत प्राप्त होते हैं जितने कि निर्वाचन क्षेत्र होते हैं । मतदाता को उतन ही मत प्राप्त होते हैं जितने कि निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधि निर्वाचित किये जान है। इसके अतिरिक्त मतदाता को अपने सभी मत एक हो उम्मीदवार को दने का अधिकार होता है। इस प्रणाली के अपने सभी मत एक हो उद्योग दक्ष हो उपनिधित प्राप्त करने की सम्मावना रहती है। इस पढिंत वा इपताचक म विधालय मण्डता एव सयुक्त राज्य अमेरिका क कुछ राज्यो म स्थानीय अधिकारिया के निर्वाचन के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रणाली का यह दौप है कि इसम बहुत स मतो के व्यय जाने की सम्मावना होती है। यह भी सम्मय है कि अल्पसर्यका का अपनी सख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाय : इसके अतिरिक्त मतदाताओ पर दिलीय अनुपात के अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जो दुस्था को प्रोत्ताहन मिलता है और अल्पसर्यका को सख्या के अनुपात के अधिक प्रतिनिधित्व के अपने वी दुसस्था को प्रतिहास मिलता है ।
- (3) एकल असरुमणीय मत प्रणाली (Single Non transferable Vote System)—इस पद्धति की विशेषता यह है कि मतदाता कवल एक ही मत का प्रयोग कर सकता है, मले ही बहुवदस्यी निर्वाचन क्षेत्र ही क्या न हो। इसका प्रयोग कुछ वर्षों तक जापान म किया गया था, अत इस जापानी प्रणाली भी कहते हैं। जापान मिबिमान दल इस पद्धित के अधीन अपनी सस्या के अनुपात म प्रतिनिधित्र मा करने में सफल हुए थे। कुछ क्षेत्र में तकति के प्रणाली मिबिमान कर इस पदिनिधित्र मा तो स्वत न उम्मीदवारों को भी सफलता प्राप्त हुई थी। यह पद्धति नी सामृहिक मतदान प्रणाली की माति दलव दी को प्रोत्साहित करती है। इसके अतिरिक्ता यह अवधानिक भी है।

साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व

साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व वे अ तगत (1) प्रत्येक सम्प्रदाय के मतदाता अपनी जाति क जम्मीदवार अर्थात हि ह हि दू को और मुसलमान मुसलमान को मत देता है। हर सम्प्रदाय के लिए उसकी जनसख्या के अनुपात में विधानमण्डल में स्थान निश्चित कर दिये जाते हैं। (1) सामूहिक सतदाताओं में ही अर्थसरपक सम्प्रदाय के तिए भी स्थान सुरक्षित कर विये जाते हैं। मतदाताओं में ही अर्थसरपक सम्प्रदाय के तिए भी स्थान सुरक्षित कर विये जाते हैं। मतदाताओं में ही अर्थ सम्प्रदाय के उम्मीदवारों का भी मत देने का अधिकार होता है। लेकिन सुरक्षित सम्प्रदाय के उम्मीदवारों में अंगन सम्प्रदाय के अधिकतस मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजयी चीपित किया जाता ह, में ही उसे अ्य सम्प्रदाय के उम्मीदवारों से कम मत प्राप्त हुए हो। मद्राप्त के 'शामा मस्यानों म परिगणित जातिया के लिए इसी माति स्थान, सुरक्षित किये जाते थे।'' साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के समर्थकों का मत्त है कि यह जीवन की वास्तविकताओं के अधिक समर्थों है और कोरे को शादकावा से परे हैं। जब सम्प्रदायों म परस्पर विद्यास एवं सहयोंग का अमाव हो तो यह कही अधिक उचित है कि उ ह पृथक प्रतिनिधित्व दिया जाय। राजनीतिक हृष्टि में अधिकसित या कम विकसित समाजा के लिए यह एक स्वस्व अतिवायता है।

लिक्षन पृथक या साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय एकता एव स्थिरता क लिए पातक है। बाधित राष्ट्रीय विकास का रय साम्प्रदायिकता के विरोध क्षेपी घटटान क समक्ष गतिहीन हो जाता है। साम्प्रदायिक एव वर्गीय हृष्टि से लोगों की सोवने की बादत पड जाती है। उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए सामा य हिता सम्बन्धी हृष्टिकोण होना आवस्यक है। क्वासित देशा का इतिहास पृथक साम्प्रदायिक निर्वाचन का समयन नहीं करता है। 1947 मे प्रारत का विभाजन पृथक निर्वाचन पढित का अवस्यम्मावी परिणाग था।

समीक्षा—अल्पसन्यका के प्रतिनिधित्व की समस्याच्या की त्या वनी हुई है। इस सम्बन्ध म डॉ अप्पादुराई का मत उपसहार के रूप में प्रस्तुत करता उचित है। उनरा कथन है कि "सामूहिक मताधिकार (unqualified joint electorates) हो नायदा है। सन्मणकाल के लिए अर्थात जब बहुमत के औलित्य म अल्पमत को विश्वास नहीं होता तो सामूहिक मताधिकार में स्थाना के सरकाण की रीति की विश्वास अर्जित करने की हिन्द स अपनाता हितकर है। इसके विषद्ध यह साभा मत तक दिया जाता है कि इस प्रणाली के अ तगत जो प्रत्याधी विजयी होता है उसम निश्चित ही साम्प्रदायिकता कम होती है स्थाकि उस सभी सम्प्रदायिक वा पर निभर रहना पड़ता ह। यह इसक वक्ष म सबल तक है।" नारत म 1921 स 1947 ई तक पृथक मताधिकार ने अप नाया गया था। भारत म साम्प्रवायिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धी यह प्रयोग इस तक के विरुद्ध एक सबल प्रमाण है जो अल्पसर्य प्रतिनिधित्व एव सरमण के लिए इसे आवश्यम

³³ A Appadorat The Substance of Politics op cit, p 479

मानते है। 1950 ई ने सर्विधान क अ'तगत मारत न सामूहिक मताबिकार क पक्ष य इस अवाधनीयपद्धतिका परिस्थायकर दिया है तथा परिगणित जातियो कलिएस्थान सुर-शित रमने की पद्धति को अपनावन्द राष्ट्रीय एकता की हुष्टि से उचित ही किया है। ³

निर्वाचन की कुछ अन्य पद्धतियाँ हितीय मतदान प्रणाली (Second Ballot)

इम पदित क अत्यात एकसदस्यी निवाचन क्षत्र होते हु । इन निर्वाचन क्षेत्रों सं क्षेत्रक एक सदस्य ही चुना जा सकता है, पर तु उसे पूक्ष वा स्पष्ट बहुमत से विजयी होना आवश्यक होता है। स्मरणीय है कि एकसदस्यी निर्वाचन क्षेत्रों में विजयी होते देखें गय है। वित्रीय मतदान हारा इस वांच को हूर करने का प्रयास किया गया है। इस पदित के आत्मात वांच प्रथम निर्वाचन में कोई उन्मीयवार स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने सकता नहीं होता तो। पुन मतदान होना है। इस वोंचारा मतदान मं प्रथम निर्वाचन में सबस कम मत पाने वांचा उन्मीवचार चुनाव नहीं तड सकता है। और प्रथम निर्वाचन में जिन मतदानोंचन में जिन मतदानोंचन में जिन मतदानोंचन में जिन मतदानोंचन में जिन उन्मीवचार को सबसे अधिक मत प्राप्त होने हैं वह विजयी मीपित किया जाता है।

इस पढ़ित म भी दाप ह (1) यह पढ़ित व्यय-साध्य ह एवं इसम अपन्यम भी बहुत होता है (2) अल्पतरफां का प्रतिनिधिस्य नहीं मिनता ह, (3) रमण म्मोर कं मृतुवार यह आवश्यक नहीं है कि द्वितीय मतदान म मतदात मिनाय रूप म मतदान करे ही। यह भी सम्बद्ध है कि एराजित उम्मीदवार अपने समयकों को अय प्रत्याशी क एका मतदान करने के लिए आधिक प्रत्येम्म प्रदान करे।

क्षा सं के बैम्बर सवन न अपन प्रविवेदन म द्विनीय मतदान की आलाबना म कहा है कि (1) इसके फ्लस्बरण सदन म दलीय स्थित दापपुण एव गलत हो जाती ह तथा विचारा एव नामक्षम की हिष्ट सं सदन म गलत एव हानिकारक सीदेवाओं होने लगती हा (2) इन सीदेवाजियों का राजनीतिक मामलों से कोइ सम्यण्य नहीं होता है। (3) दितीय मतदान की सम्यावना के कारण प्रथम मतदान ने परिणाम असत्य होते हैं। अधिकांश मतदाता प्रथम मतदान म महानुभूति एन वैयक्तिक हिष्ट सं मतदान करते हैं। (4) द्वितीय मतदान म व अपन राजनीनिक विचारा के अनुसार मतदान करते हैं। (4) द्वितीय मतदान म व अपन राजनीनिक विचारा के अनुसार मतदान करते हैं। (4) द्वितीय मतदान म व अपन राजनीनिक विचारा के अनुसार मतदान करते हैं। (5) द्वितीय मतदान करितक व्यय का एक कारण्य होता है। (5) द्वितीय मतदान अतिरिक्त व्यय का एक कारण्य होता है। (दितीय मतदान की सम्मावना के कारण फात के चतुष गणतान य निचन उम्मीदनार निर्वा चनी से दूर रहते ने 13 उपरोक्त सनी दाप कास वर विश्लेष स्प स सामू हान है।

³⁴ A Appadoras The Substance of Politics, op cit, pp 480 481

³⁵ Finer op at, pp 553 554

बहुदलीय पदित के परिणामस्वरूप निवाचनों म प्रचलित अप्टाचार के बारण का स म राजनीतिक स्थिति वढी दयनीय थीं। प्रथम एव दितीय मतदान के बीच म विमि न दला में अनुचित चुनाव गठव घन हो जाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण है। फा स म निवा चित सदस्य को 'अल्पसरयक का व दी' (Prisoner of the Minority) की सभा दी जातो है। 1919 ई के पूज जमनी म विधायकों के लिए 'कुह डेल' (Kuhhandel) सब्द प्रचलित था। इसका अप 'राजनीतिक दलों के (मध्य') पशुओं की सौदेवाजी' है। फाम्स म दितीय मतदान का अत्यधिक प्रचलन है। उदाहरण के लिए, 1889 ई स 211 बार 1896 म 178 बार, 1902 म 174 बार, 1928 म 425 बार, तथा 1936 में 424 बार द्वितीय मतदान डुआ था। ¹⁸ इसके दोधों को दूर करने के लिए वैक्तिएक मठ (Alternate Vote System)

इस प्रणाली के अ तगत केवल एक ही निवाधन होता है। मतदाताओं का विशिन उम्मीदवारा में से अपनी पस दगी "यक्त करने की सुविधा होती है। यदि प्रयम पस दगी का उम्मीदवार सफल नहीं होता है तो उसकी दितीय एव ततीय पस दगी को सबसे अधिक मत माने वाले उम्मीदवारों में विमाजित कर दिया जाता है। एक ही निवाधन में दो मतदान होते हैं। इससे उन्हरें खच एव निवाधन के फ्रमटा स तो वच जाते हैं पर्तु निवाधन के पूज विभिन्न दसों म जो दलीय सौदेवाओं होती है उसका अत नहीं होता है। लेकिन इस पद्धित से अस्प्रयम्भ की स्थित इड हा जाती है। एन

व्यावसायिक प्रतिनिधित्व

प्रविधिक एव क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की तीय आसोचना की गयी ह । नुछ विचा-एको ने उसने विपरीत व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समयन किया है । इसके प्रवध्य विधानमण्डल म क्षेत्रा के स्थान पर व्यवसायों को प्रतिनिधित्व का आधार यनान के समयक हैं । व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के पक्षधरों का तर्क यह है कि एक क्षेत्र के विभिन्न व्यवसायों एव पैशा में सलान सभी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व की न का एक प्रतिनिधित्व की अपन पृषक समुदाय होत ह । एक पने के व्यक्ति अपन सं सम्बिधत सभी समस्याना को नकी प्रकार जानत ह अंत प्रतिनिधित्व का सही आधार पणा, पणा, वन या व्यवसाय ही हो सकता ह । यवसाय हो प्रतिविधि का स्वामिविक कामार है, योत तो इंपित्र एव राजनीतिक आधार है। अत व्यावसायिक प्रतिनिधित्व क समयक निर्वाचन योत्रों के स्थाना पर व्यावसायिक प्रमुत्ती के प्रशिविधित्य के समयक

³⁶ Ibid , p 554

³⁷ Ibid

है। गिरुड समाजवादी विचारक जो डी एच कोल के अनुसार "व्यावसायिक प्रति निधित्व ही सच्चा लोक्ताणिक प्रतिनिधित्व है।" अध्याप निर्वाचन निर्वय ही जनोक्त श्रीय है 123 ससद समस्त नागरिका का सभी विषया म प्रतिनिधित्व का दावा बरती है। लेक्नि वास्तय म वह किसी का प्रतिनिधित्व नही करती । वह राज नीनिय लोकतात्र व स्थान पर व्यावमायिक लोकतन्त्र का प्रतिपादक था।

व्यावसामिक प्रतिनिधित्व की धारणा यहत पुरानी नही है। केन्द्र राजनीतिश मिराबू एव विदान सेईज (Seises) व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। राज नीतिक रूप म इत्र विचार रुसो के 'सामाजिक समभौत' म मिसते हैं। " वतमान समय म दग्ई (Leon Duguit), कोल, ग्राहम वालास, वेब-सम्पत्ति (सिटनी एव बेट्सि वय) इसके समयक थे। गिरुड समाजवाद एव उसवा प्रमुख विचारक कोल इसवे प्रमुख प्रतिपादक व । कोल आयिक जीवन का राजनीतिक जीवन स पणत पुषक करने एवं व्यावसायिक एवं आर्थिव कार्यों को व्यावसायिक संघा का सौपने का पन पाती था। उसने प्रत्यक व्यवसाय के स्थानीय और राष्ट्रीय सथ बनाने का सभाव दिया था। प्रत्येक सप अपने व्यवसाय का प्रवाध करने के लिए स्वतान था । गिरुड समाजवादिया ने इन सब व्यावसायिक सघी के ऊपर उनके व्यावसायिक एवं आर्थिक सम्बन्धों के नियात्रण हेतु एक नवीन सस्या 'ब्यावसायिक याय को सर्वोच्च लोकत त्रीय "प्रामालय (Democratic Supreme Court of Functional Equity) के निर्माण का सुनाव दिया है। 13 प्राहम बालास दितीय सदना म व्यवसाया का प्रतिनिधित्व देने का पक्षपाती था। इगुई व्यवसाय, वाणिज्य, उद्योग घ घा को ही नही अपित विनान, धर्म आदि को भी प्रतिनिधित्व दिये जाने का समयक या । वेब दम्पति दा समदा-राजनीतिक एव आधिक-के निर्माण ने पक्षपाती थे।

व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के टोप

(1) इसका क्रिया वन कठिन है। व्यवसायो का वर्गीकरण एव व्यवसाया के आधार पर जनसदया का विमाजन सथा प्रत्येक व्यवसाय का प्रतिनिधित्व एक समस्या है। अत यह प्रणाली भ्राविष्ण है।

(2) इस पद्धति का आधार ही मलत है। मनुष्य मूलत आर्थिक प्राणी नही है। आयिक हिता का जीवन म बहत महत्व है, पर द वे ही सब कुछ नहीं है। इसक

G D H Cole Refer to Coker Recent Political Thought, 1934, pp 266 67

³⁹ Thid

⁴⁰ Cole Social Theory, 1920 p 207 41 Finer op at, p 222

⁴² Cocker F W op cst. p 278

अतिरिक्त राज्य का काथ केवल आर्थिक हिंता का सरक्षण करना हो नही है। प्रति-निधित्व ब्यक्ति के समग्र रूप अर्थात नागरिक का होना चाहिए। मेरियट के अनुसार व्यक्ति केवल डाक्टर, वकील अथवा लुहार नही है। एक नागरिक का तो इनसे अधिक महत्व है।¹³

(3) व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के फलस्वरूप वग हितो की प्रवानता एव प्रमु-खता हो जाती है तथा राष्ट्रीय हित गोण हो जाते हैं । विवानमण्डल वर्गीय स्वाय-साधन की पूर्ति हेतु सथय-स्थली वन जाते हैं । इस पद्धति म सथय को वढावा

मिलता है।

(4) दलीय पदाति के विकास के वारण व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है। प्रत्येक रूल को आधिक नीतिया होती है, उनम विभिन्न व्यवसाया से सम्बर्धित व्यक्ति होते ह तथा व विभिन्न व्यवसाया के हिता की रक्षा करते है।

सोवियत सविधान (1924 36) श्यावसायिक प्रतिनिधित्व पर आयारित या और नगरों के प्रत्येक उद्यम एवं सस्या म निर्वाचन होते थे।

³ Marriot The Mechanism of Modern State, Vol I, p 505

⁴⁴ Finer op cit, p 222

31

लोकमत F PUBLIC OPINION 1

आधुनिक लोकत त्रीय पद्धति से लोकसत का व्यापक सहस्य है। साबसीस यसक संतापिकार, राजनीतिक दलीय पद्धति का विकास एव सगठन तथा लोकप्रिय लाधार पर विधानमण्डला के निर्माण के फलस्वरूप विकास एव सगठन तथा लोकप्रिय लाधार पर विधानमण्डला के निर्माण के फलस्वरूप विकास का स्वात विद्या है। लोकसत राजनीति शास्त्र का विगत बद्ध शताब्दी स अध्ययम का एक प्रधान विषय स्टा है पर जु उत्तकों कोई शास्त्रीय परिमाधा प्रसुत नहीं की जा सकी है। प्रसिद्ध स्पेनिया विषयारक जोसी लोरहीना ए गस्टेट (Jose Ortega Y Gassett) का सत है कि विशव म क्सी वो मी कमी लोकमत के अतिरिक्त किसी अप पर शासन की आभारित करने शासन नहीं किया है। यह एक कट्ट सच्च है। सभी सरकारे, चाहे दे कितनी ही अटट गयो न रही हो, जयनी सत्त के निर्ण लोकमत पर निमर रहती हैं। लोकती ही अटट गयो न रही हो, निरकुश एव अधिनायकवादी सासन भी दीघकाल तक लोकमन मी शोस करने म असकत रहने हैं।

लोकमत का अथ

I Jose O Y Gassett The Revolt of the Masses, cited by E Asirvatham Political Theory 1965, p 482

अनुसार राय प्रकट करता है और अपने मत पर दृढ बना रहता है। प्राय इस प्रकार को मत विभिन्नता के कारण लोकमत का निर्माण नहीं हो पाता। प्रत्येक दल या वग अपने-अपने दिष्टिकोण से विचारों का प्रचार करता है। अपने मत के समथन म वह प्रत्येक प्रकार के सही एवं गलत तरीका और आँकडा का सहारा लेता है तथा बहमत को अपने पक्ष म प्रमावित करने का प्रयत्न करता है। जो प्रभावशाली ढग से अपन विचारों का प्रचार कर पाता है उसी की तरफ जनता अधिकाधिक उ मुख हो। जाती है एव साधारणत ऐसा मत बहसरयक की राय वन जाती है और वही लोकमत कह लाने लगती है। पर त बहमत लोकमत नहीं होता है। लोकमत से तात्पय तो समाज नी राय से होता है।

लोकमत की विभिन्न विद्वाना न भिन्न भिन्न परिभाषाएँ प्रस्तुत की है। ब्राइस² के अनुसार "लोकमत उन सब इष्टिकोणा के योग के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो जनता द्वारा सावजनिक हितो से सम्बद्ध विषयो पर व्यक्त किये जात ह । इस अय म वह सभी प्रकार के विश्वासा, घारणाआ, पूर्वाग्रहो एव आकाक्षाआ का सम्मिश्रण है।" एल डब्ल्यू डोव॰ के अनुसार "लोकमत से तात्पय किसी सामाजिक समृह के सदस्यो की किसी प्रश्न विशेष के प्रति प्रवित्त स है। सार समृह से सम्बध्यत प्रश्ना के सम्बध में अपेक्षाकृत प्राथमिक विचारा की सामूहिक अभिव्यक्ति ही लोकमत है।' अमरिकन मनोविज्ञान शास्त्री किम्बाल यग के अनुसार "लोकमत से अय किसी समय विद्रोप पर जनता के विचारा से है।" मीरिस जिसबग के जनसार "लोकमत जमेक व्यक्तिया के विचारो की प्रतिक्रिया का सामाजिक प्रतिफल है। "

उपरोक्त परिमापाओं के यह स्पट्ट है कि लोकमत की परिमापा के सम्बंध म विद्वान एकमत नही है। विलहेम बोयर (Wilhelm Bouer) न 'वास्तविक लोन-मत' एव 'जनता म प्रचारित मत' से भेद किया है। जनता म प्रचारित मत विशुद्धत वैयक्तिक होता है। लोकमत इसके विपरीत सामाजिक सावयवी बक्ति है। समूह

[&]quot;Public opinion is the aggregate of the views men hold regarding matter that affect or interest the community '-Lord Bryce Quoted B B Majumdar op cat, p 283

[&]quot;Public opinion refers to people's attitudes on an issue when they are members of the same social group "-I, W Dobb Public Opinion and Propaganda, p 35

Public opinion consists of the opinions held by a public at a certain time "-Kimball Young A Handbook of Social Psychology, 4 1957 pp 431-32

Public opinion is a social product due to the interaction of many minds '—M Ginsberg The Psychology of Society p 145 Wilhelm Bauer Public Opinion, cited by E Assivatham op cit 5

^{(1965),} p 483

क्तिक एव प्रयक प्रयक भावनाओ एव बास्याओं को लोकमत संशोधित करके समाज की इच्छा का रूप प्रदान करता है। अत लोकमत केवल विचार एवं सिद्धा त मान न होनर समूह विशेष की सामूहिक आस्या एव विश्वास होता है। रोसेक (Roucek) के अनुसार लोकमत के चार अनिवास तत्व हैं प्रथम, समह या जनता, दितीय, जन-समूह के सदस्या के समक्ष अपने मामान्य हितो से सम्बाधित समस्या या समस्याएँ जिनके सम्बाध मान आपस मानिचार निमश कर सक, तृतीय, समूह का नेता एव नेताओं का वर्ष जो महत्वपूर्ण प्रश्ना के सम्बाध म सामृहिक मत के निर्माण म योग दे सके एव जनता का ध्यान प्रस्तावित मत को स्वीकार करने के लिए आकर्षित कर सके, तथा चतुर्व, जनता द्वारा समाज के नेता या नेताआ द्वारा प्रस्तावित मत की स्वी कृति एव तदन्रूप कार्य को स्वीकृति प्रदान करना । सक्षेप म, लोकमत किसी विशिष्ट वग का हित न हो कर जनसाधारण का मत होता है। वह लोक कल्याण की भावना स प्रेरित विवकी एव स्थायी विचार है। गेटेल ने नोकमत की अत्यात तकपूण समीक्षा की है। उसका कथन है कि

विरोप की स्वायपरक क्षणिक भावनाओं के स्थान पर मामुहिक विवेक शक्ति एव नत्याणकारी मामा य इच्छा की अभिव्यक्ति ही लोकमत है। जनता की क्षणिक वैय-

जिसे लोकमत कहा जाता है वह न तो लोक या जन (public) ही है और न मत (opinion) ही है। समाज म जो मत प्रचलित एवं मा य होता है वह वास्तव म ममाज के अल्पसरयक या कुछ प्रमुख नताओं या सम्बर्धित वर्ग विशेष का मत होता है। जनता अधिकतर मावजनिक प्रश्ना म विशेष रुचि नहीं लंदी है। यह कहना अधिक ठीक है कि जनता तो अनानी होती है या उस पूर्व सूचता भी नहीं होती जत दस हरिट से स्रोक्रमत जनता का मत हो ही नहीं सकता । इसके अतिरिक्त एक ही साव जिनक प्रकृत पर परस्पर विरोधी यत या विचार पाये जाते ह जो एक दूसरे का खण्डन करते है। ऐसी स्थिति म जनता के मामान्य मत के निर्माण की आशा मुग-मरीचिका है। यदि ऐसा कोई मत होता भी है तो उसे लोकमत की सना नहीं दी जा सकती । यदि वह लोकमत है भी तो भी हम उसे जनता के अस्पट एवं अध्यवस्थित विचारा ना समूह कहम । जनता विचार करन समय परम्परा एव रीति रिवाज से प्रमावित होती है। योडे से ही व्यक्तिया म वि तन एवं मनन की वह प्रतिमा पायी जाती है जो सावजनिक ममस्याजा को सुलकाने के लिए आवश्यक होती है । अत अनक तथावधित लोकमत तो पूर्व धारणाएँ, विस्ताम, शोध्यगामी निष्कप एव पर-स्परागत विचार मात्र होते हैं। जनता का एक वडा माग स्वय समस्यात्रा पर विचार नहीं करता ह अपित दूसरा के विचारा ना सहज रूप म स्वीनार नर तेता है। सत्य

Roucel J S Twentieth Century Political Thought, cited by E Asirvatham op cit, p 482 Gettell Political Science, 1956 pp 284 86

ता यह है कि लाकमत का निर्माण नेताओं का छोटा समूह करता हे एवं जनता उनके निणय एव सुभावा को स्वीकार कर लेती है। लोकमत की श्रेष्टता नेताओं की दुदि-मत्ता एवं निस्वायता पर निमर करती है। एक सगठित अल्पमत सदैव ही यह प्रद-चित करता रहता है कि उसका मत बहुमत का मत है या लोकमत है।

दाँ आशीर्वादम⁸ न लोकमत का मूल्याकन करते हुए यह मत व्यक्त किया है कि सच्चे एय भूठे लोकमत में नेद करना लोकमत को दमन का अस्न बनने से रोकन एव उसे मनस्वायक बनान के लिए आवश्यक है। आधुनिक समाज में लोकमत के निर्मण के लिए अनेक कृतिम एव अवादनीय साननों का प्रयोग किया जाता है। दवाव एव हित समूहा द्वारा अपने स्वायाँ एवं हितों को पूर्ति के लिए ऐसे अनेक काय एवं प्रवाद समूहा द्वारा अपने स्वायाँ एवं हितों को पूर्वा के लिए ऐसे अनेक काय एवं प्रवाद किये जाते हैं कि जनता इन समूहा के वर्षीय एवं निजी हिता को जनता का हित समभ बैठती है और अल्पवर्गीय हितों के विचारों का अनजाने ही समयन करने लगती हैं। इस प्रकार लोकमत का निर्माण करने वाले दवाव या हित-समूहों द्वारा जनता के समक्ष कल्पित मय, सम्मावनाता, चूणा एवं विचारों का प्रवान इस प्रकार किया जाता है सनका तनता सहज ही उनके प्रचार का विकार हो जाती है। सामा यत अनेक दल जो लोकत न म कोई आस्या नहीं रखते हैं, लोकत न की दुहाई देते हुए देखा जाता है। उनके द्वारा जनता की खुशामद की वाती है एवं उसे जाल म फैसाने का हर सम्मय प्रयास किया जाता है।

लोकमत के निर्माण एव प्रसार के साधन

वतमान राज्यो में लोकमत के निर्माण एव प्रसार के प्रमुख साधन निम्नत हैं

(1) व्यक्ति का स्वज्ञान—स्थिक्त परिवार का सदस्य होता है। पारिवारिक सम्बाधा एव सामाजिक जीवन क अनुभवा से व्यक्ति को वास्तविक जरात का ज्ञान होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन म अपने पेसे एव अ य कार्या के दौरान अनेक प्रकार के व्यक्तिया ने सम्बन्ध न जाता है तथा अनुभव प्राप्त करता है। राजनीतिक सगठन, अधिकारिया, डाकजाना रेल, अ य यातायात, पुलिस, सेना आदि के सम्बन्ध में बहु देखता एव अनुभव करता है। अनक बातें वह सुनता एव पढता है। इससे जसे इनका ज्ञान होता है। वह कर देता है, अवालता के सम्बन्ध म बाता है तथा राज्य के कानून का उल्लाम करने पर अपराधिया को विच्छत होते हुए देखता ह । सिनेमा, रेडियो आदि ज्ञान के आधुनिक महत्त्वपूष साधन है। व्यक्तिया को स्व अनुमन स प्राप्त यह ज्ञान उहे सावजिनक मामको के सम्बन्ध म विचार या मत निर्धारित करने म योग देता है। इसके अविरिक्त प्रत्येक समाज म विभाग योग्यताओ एव ष्रमता वाले व्यक्ति होते हैं, जैसे—दाविन , साहित्यकार, पत्रकार, विधायक, समाज पुषा रक एव राजनीतिक नेता आदि। इनके हारा समय-समय पर सामयिक सामाजिक होता आदि। इनके हारा समय-समय पर सामयिक सामाजिक

⁹ E Asirvatham Political Theory, 1965, pp 485 89

समस्याओ पर विचार प्रकट किय जाते हैं। जनसाधारण इन विचारा स भी सावजनिक समस्या के सम्बन्ध म जपना मत निश्चित करने म प्रमाबित होता है । समाज क सभी थेणी के मनुष्य लोकमत के निर्माण म अपना-अपना योग देते हैं । परिवार म व्यक्त विचार लोकमत के निर्माण म सहायक होत हैं। इस प्रकार क विचारा की दा मुर्य विशेषताएँ हैं--प्रथम यह स्वत व धनकारी (compulsive) होते है. एव दितीय, यह कृपाल एव उपकारी (Lindly) होत ह। समाज-सुधारका ने परिवार को लोकमत के निर्माण की एक प्रधान इकाई माना है। फाइनर¹⁰ का मत है कि इसी कारण या तो सोवियत रूस की भाति जिस प्रकार प्रारम्भ म परिवार का समान्त करने का प्रयास किया गया था उसी प्रकार परिवार को नष्ट करने का प्रयत्न विया जाता है अथवा नाजी एव फासीवादिया की मांति पारिवारिक अनुशासन को शिथिल करने के प्रयत्न किय जाते है। जो स्ती एव पुरुष विसी उद्योग एव घ वे या रोजगार म काम करके जीविकोपाजन करते है वे अपने काय के दौरान उससे सम्बन्धित अनक बातो एव सम्बंधा का नान प्राप्त कर लेते हैं। कमचारी सथा, सहकारिता सस्याक्षा एव श्रमिक सबी की स्थापना ने उस ज्ञान के प्रसार म अयक बोग दिया है जो सावजनिक कार्यों के सम्पादन म सहायक होता है। इत थमिक सघी एव हित समूहा न साव जिनक क्षेत्र म जो भूमिका निमाई है उसके परिणामस्वरूप राजनीति शास्त्र म व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धा त का विकास हुआ है। इस सिद्धा त का प्रतिपादन श्रम सथवादिया (Guild Socialists) द्वारा किया गया था ।

लेकिन सावजनिक मामला से सम्बाधित मुख्य झान प्रतिवदनो एव सूचनाओं से प्राप्त होता है। आधुनिक समाज से सावजनिक धिसा एवं प्रचार के साधनी में राजनीतिक दका के परचात प्रमुख स्थान पुस्तकों, समाचार परा, विद्यालयां, बलवां, चल (धार्मिक संगठनों), सिनेसा, रेडियां एवं जन चर्चों को प्राप्त है। 11

(2) राजनीतिक बल—लोकमत के निर्माण म राजनीतिक बतो की भूमिका बहुत ही महत्वपूण है। जाककल लाकत नात्मक देशों म एक स अधिक वल होते है। वे अपनी मा यताओं एव अपने हिस्टकाणों के अनुसार विमिन्न सायजिनक प्रस्ता पर सावजितक रूप स दियोग समाओं म विचार ज्यक्त करके, समाचार परा म लेख जिसकर एव विधानमण्डला म सासन की गीतिया को आलोचना करते जनमत का ज्यवस्थित एव स्पिर वनाने में सहायता करते है। हर दस प्रत्येक समस्या पर अपने निचार जनता के समक्ष रखता है। बनता विभिन्न प्रकार के विचारों को मुनकर सर लता से अपना मत निविचत कर लेती है। विचान के समय म दलीम प्रमार अपनी चरम सीमा पर होता है एव इस समय प्रत्येक सम्वा द विचार करने ती है। विचान को समय म दलीम प्रमार अपनी चरम सीमा पर होता है एव इस समय प्रत्येक दस अत्यीक सिमा होता है। आध-

¹⁰ Finer op at, 1956 p 261

¹¹ Tiner op at, 1956, p 263

निक मतदाता क लिए बतमान सामाजिक परिस्थितिया के स दम म राजनीतिक दत्ता ने सहसोग के अभाव म सायजनिक समस्याजा म महत्वपूण योग दे सनना सम्मय मी नही है । सभी व्यक्ति वतमान मिलस्पर्धा प्रधान समाज म अपन जीवन की आव-स्थकताजा की पूर्ति म इतन सलग्न होत हैं नि उह सावजनिक समस्याओ सम्बन्ध सम्मूण मूचना प्राप्त करके निषय कर सकना किन्त होता है। राजनीतिक दता द्वारा मतदाताजा न समक्ष सायजनिक जीवन की सम्बन्धित विभिन्न प्रदन्ता पर आवस्यक सूचनाएँ प्रस्तुत की जाती हैं और मतदाता उन विभिन्न सुवनाथा के आधार पर जपना मत निश्चित करत है। दत्ता के द्वारा विभिन्न सामाजिक एव राजनीतिक समस्याजा के सभी पहल्ला को जनता के दमक्ष पुणक्षण स्पष्ट कर दिया जाता है।

हरमन फाइनर ने दल को राजा की सजा दी है। दला के द्वारा व्यक्तिगत विचारा एव मतो से पृथक सामूहिक रूप में समस्या पर सामूहिक मता एवं विचारा की उपस्थित किया बाता है। विभिन्न दल वैकल्पिक मूल्य, माप्टण्ड एव समाधान प्रस्तुत करते हु। विभिन्न विचारा म किसका प्रायमिकता दी जाय, यह भी उनक द्वारा सुभाया जाता है। राजनीतिक प्रश्ना पर मत निर्धारण विशिष्ट राजनीतिक प्रशिक्षण के अति रिक्त अनेक स्वामाधिक गुणा जिन्ह हम रुचियाँ (aptitudes) कहत है और जिनका अधिकाशत अमाव ही होता है, से अधिक सम्बन्धित है। जनता स्यचेतन नहीं होती है। उन्ह सजग एव बेतन बनाने के लिए किसी सस्या या अधिकरण की जावश्यकता होती है। निर्वाचन-काल भ तो विचारा को केद्रित करने की विशेष रूप से आवश्यकता -होती है। यह दायित्व राजनीतिक दला द्वारा पूण किया जाता है। वे सम्पूण राष्ट्र को बा पुत्व की डोरी म बाध देत हैं, व्यक्तिगत नागरिका को राष्ट्रव्यापी दिन्द प्रदान करते हैं, सावजनिक प्रश्ना से सम्बध्ित सम्पूण ज्ञान एव सूचना की एकनित करके जनता ना लोकमत के निर्माण से नेतत्व करते हैं। कुछ देशा म--जसे, सोवियत रूस, चीन आदि साम्यवादी देशो---म एक-दलीय पद्धति है। वहा दल की सदस्यता दश की कुल जनसच्या के थोडे से ही व्यक्तिया को प्राप्त है। इन देशा में लोकमत शीयस्य दलीय नेताओं क विचारा एवं दृष्टिकोण का प्यायवाची मात्र होता है। भारत के सम्बाध मंगह सत्य नही है। लोकमत का अर्थ यहा केवल काग्रेस उच्च सत्ता के विचार एव नीतिया नहीं है।

(3) समाचार पत्र—आपुनिक समाज म लोकमत के निमाण एव प्रसार म समाचार-पत्रा द्वारा प्रमुख भूमिका निमाई जाती है। समाज के दिक्षित व्यक्ति प्रति-दिन अखबार पढते है। प्राय हर पाठक अपनी रुचि ने समाचार पत्र की विचारधारा से प्रमावित होता है। जनता का सावजनिक समस्यानों के सामाजिक, आर्थिक एव राजमीतिक दिष्टिकोणा के सम्बाध या विभिन्न समाचार-पत्रा द्वारा नान प्राप्त होता है।

^{12 &}quot;Party II King"-Finer op cit, p 274

892 | आधुनिन चासनतः म सावजनिक समस्याना पर विभिन्न लस एव सम्पादकीय टिर्णाणयां प्रकासित हाती हैं। यह पाठका व विनास को प्रमायित करते हैं, चेक्नि स्वस्थ लाकमत क निर्माण व तिए स्वतंत्र समाचार पत्रा की आवस्यकता है। अधिकात देशा म स्वित इससे मिन्न है। समाचार पत्र जगत म नी साम्राज्या भी स्वापना हुई है। मास्त म सभी प्रमुख समाचार-पत्र वहे-चहे उद्योग परिवारा सं सम्बन्धित हैं। विरता पुप क प्रमुख समा चार-पत्र है दि दुस्तान टाइम्स (अंग्रजी), हि दुस्तान दैनिक एवं साप्ताहिक (हिंदी)। टाइम्स आफ मुख व वई असवार हैं। इण्डियन प्रसन्नेत के कई सक्करण प्रवासित होतं हैं। उपरोक्त सभी पत्र पूजीवादी खोनत त्रीय दिस्कोण ना प्रतिनिधिस्त करत हैं। लोकतान्त्रिक समाजवादी विचारधारा का प्रतिनिधिस्य वस्ते वाल स्वतंत्र समाचार पत्रा का सबया नमाय है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक राजनीतिक दल का अपना समावार-पत्र हैं। उदाहरण के लिए स्वराज्य (स्वता म दल), नवानल हैराल्ड (काग्रस नासकीय), मदरलंग्ड वावज्ञ य (जनसप), पद्रियट (साम्यावादी दन)। विभिन्न समाचार एजे सिया के होरा विभिन्न समाचार पत्रा क पाठका के विचारा का समाचारा के तौरत्तरीका हारा निविनत क्या जाना है। समाचार-पत्र के द्वारा जिस सीमा तक निप्यसता एव स्वत त्रता का अनुगमन किया जाता है, उसी सीमा तक स्वस्य जीकमत का निर्माण भी सम्मव है। लेक्नि इसक साथ-साथ यह भी थावस्पक है कि समाचार पना द्वारा स्वत वता का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उनम प्रकाशिव वेदा उत्तरवासित्वपूरण एव समाचार तथा सुचनाएँ प्रामाणिक हाने चाहिए। समाचारा की सुचना इस प्रकार देनी बाहिए कि जनता जनका मतत अब न लगाये और न अमित हो। समाज म विद्वेष एवं कलह उत्पन करने वाली एवं समाज के निवक स्वर को गिरान वाली प्रध्य ६४ फण्ड ज्यान करा गाण प्र प्रचनावा को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। वतमान वाल म प्रेस की निप्पसंता एव प्रभावना का त्रमायक वहा भएता आहर । यथावदादी दिव्दकोश सं जनता का विश्वास हृदता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण वनायनाथा वाल्काम् । वालकाम् । वाल्काम् । वाल्काम् । वाल्काम् । वाल्काम् । वाल्काम् । वालकाम् । वाल्काम् । वाल्काम् । वाल्काम् । वालकाम् । वाल बहर प्रमा का प्रयोग अपने स्वार्थों की पूर्ति से लिए करते हैं। व कुछ सुबनाओं की प्राप्त छोड दते हैं एव कुछ की तोड मरोड कर प्रस्तुत करते हैं। इसस स्वस्य लोक-मत क निर्माण म बाधा उत्पन होती है और जनता श्रीमत हो जाती है।

13

\$ 1 विका

विद्यान

सामा व

समात्र हो \$1 m बनना इनत नेवार काना मेंनी है निर्मा

इसके अतिरिक्त धार्मिक सगठना—वर्चे, मसजिदे, धार्मिक समाज—का लोकमत क निर्माण एवं प्रसार म महत्वपूर्ण नाग होता है। अनेक देशा म नहाँ पम को आज भी मा यता प्राप्त हैं, लावमत के निर्माण में इन संस्थाना द्वारा मिक्किय भाग निया वाता है। अनेन मुस्लिम देशा में बाज भी राज्य, सम्मत्ति, निवाह, उत्तराधिकार, हित्रमा एव विश्वमिमा ने सम्बन्ध म मध्यमुगीन निचार प्रचलित हैं। अनेन मुस्तिम देशा म हित्रमा की मुक्ति का आ दोलन सिक्रम है परतु भारत म मुक्तिम समाज जाव भी बहुपत्नी प्रधा व विरुद्ध विधि बनाय जान का समयन करने के लिए तयार नहीं हैं। मुस्तिम कानून म सन्नाधन के मौतिक विचार को अलोकत नीय कह कर अस्य

सस्यक पुरातन मुल्ला प'यो मुस्लिम नतृत्व द्वारा विरोध किया जाता है, जबिक सत्य यह है कि प्रगतिशील धम निरपक्ष समाज म सामाजिक अत्याचार से व्यक्ति की रक्षा करना राज्य का प्रधान कतन्य है। हिंदू समाज म जाति भेद ना कलक आज भी विद्यमान है। मध्यपुगीन एव अपगतिशील आस्या एव विश्वास जनित समाज, जाति प्रया, पुरात ने म न्वमुल्लापन आदि स्थितियाँ स्वस्थ लोकमत क निर्माण म वाधक होती है।

(4) दबाय या हित समूहों क द्वारा भी लाकमत के निर्माण को प्रभावित किया जाता है। अमेरिका म द्याव समूहा द्वारा विभिन्न तरीका स सम्बी बत विषया म विधि-निर्माण को प्रमावित करने वे लिए प्रचार काय किया जाता है। इते लाबी इग (Lobbying) कहते है। सम्बी घल समूहा द्वारा अपन हित विरोधी विधिया के निमाण को रोकन का हर सम्भव प्रयत्न किया जाता है एव एसी विधियों को पारित कराने का हर सम्भव प्रयत्न किया जाता है जिनसे उनके हित का सबधन सम्मव है। सकुक्त राज्य अमेरिका म इस हेतु वैतनिक प्रचारक नियुक्त किये जात है एव वे विधा यका वो प्रमावित करने का हर सम्भव प्रयत्न करते है। सकुक्त राज्य अमेरिका म इस हेतु वैतनिक प्रचारक नियुक्त किये जात है एव वे विधा यका वो प्रमावित करने का हर सम्भव प्रयत्न करते है। सकुक्त राज्य अमेरिका म स्थायार, उद्यान, कृपि, उत्पादको, श्रीमको, जल्पसयको आदि के सथ है जो जपन हिता के रखाय सतत् रूप म नियाशील रहते है। बारत म दवाव समूहो का संयुक्त राज्य अमेरिका की भौति उदय एव विकास नहीं हुआ है, फिर भी देश म उद्योगो एव कृपन वन क दवाव एव हित समूह सिवय है। व्यक्तिमत उद्योग द्वारा प्रयक्त पक्त वा की दिता है। जी हिता की जीति है।

दबाब समूह की व्यवस्था हानिकारक नहीं होती है। सुशासन मं शासनकी नीतिया के प्रति जनता की प्रतिनिया एवं दृष्टिकीण की गात करने का प्रयत्न किया जाता है। इस दृष्टि स दयाब समूद पक्ष विदोष के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दबाब समूहा के विचारों को हम स्वस्थ सीकमत नहीं कह सकते हैं बयाकि वे समाज के एक बग विशेष का हित होते ह न कि जनसाधारण के हित ।

इसके अितरिक्त नागरिक सघ एव सस्थाएँ, विद्यालय, महाविद्यालय, विदव विद्यालय, साथ सस्थान, साहित्य, टेसीविजन, रेडियो एव सिनेमा, सावजनिक समाए, सामाय निर्वाचन एव विधानमण्डस भी लोकमत के निर्माण मे योग देते हूं। साहित्य कामाज का दपण होता है। शिक्तित नागरिका पर साहित्य का प्यान्त प्रमाय पड़ता है। दिलित नागरिका पर प्राह्मिक का साहित्य का प्यान्त करना साधन हैं। देलीविजन, रेडियो एव सिनेमा सचार एव प्रचार के आधुनिकतम साधन हैं। जनता इत्त पर्यान्त प्रमाय पड़िया अपनी चरम सीमा पर होता है। सामाय निर्वाचन काल म राजनीतिक दलीय प्रचार अपनी चरम सीमा पर होता है। जनता जिस दत्त के कायकम को उचित सम नती है निर्वाचन में उसी दल के सम्मीदवार को मत देवी है। विधानमण्डल में वजट एवं सामा य प्रस्तावा पर शोने वाली बहुस भी लोकमत के निर्माण म सहायक होती है।

स्वस्य लोकमत के निर्माण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ स्वस्य लोकमत के निर्माण य निम्नानित परिस्थितियाँ याग प्रदान करती हैं

सभी तथ्य एव मुचनाएँ ठीक ठीक उपतव्य होनी चाहिए।

(2) समाज र नेताओं का दृष्टिकोण संतुलिन, शांत एवं परिपन्त होना पाहिए।

(3) जनता सुरिधित, विचारवान, पूर्वाप्रहा एव मायताओं से मुक्त तथा चित्तन की प्रवृत्ति हो युक्त होनी चाहिए। अधिका एव निधनता स्वस्थ सोकमत के निर्माण म चहुत वडी बाधार्ग हैं। समाज म आर्थिक समानता और द्योपण का अमाव होना चाहिए।

(4) राजनीतिन दला, थामिक सपा, थामिक एव साम्प्रदाविक तथा भाषायी य जातीय सस्याना का अपने सदस्या पर कठोर नियाचण नही होता खाहिए।

(5) समाज म असामाजिक एव जन विरोधी प्रवित्तयों को नहीं पनपन देना चाहिए।

(6) समाचार पत्र स्वतः त्र तथा सनत रूप म जागरूक एव निजक्ष होन

चाहिए।

(7) दलीय व्यवस्था लोकत त्रीय हानी चाहिए एव जनकी कायपदिति भी पूणक्ष्यण लोकत त्रीय होनी चाहिए। नकीण, वर्षीय एव साम्प्रदायिक दला पर प्रतिव प समा देता चाहिए। विरोधी दलो को प्रचार की पूण स्वत त्रता होनी चाहिए।

(8) ब्यक्तिगत स्वत तता एव विचार-अभिन्यक्ति की अनिया तत स्वतन्त्रता

होनी चाहिए।

स्रोक्तनत का पता तथाना कठिन होता है पर तु स्वस्थ लोकमत ही वह आधार दिला है जिस पर सोकत न के स्थायी मवन का निर्माण सम्बद है। सोकमन एव सामान इच्छा समानार्थी होने चाहिए। यदि लोकमन का कोई महत्व एवं मुख्य हो सकता है तो वह प्रघुढ, बोधनाम्य एवं व्यापक आधारसुक्त होना चाहिए। 12 लोकमन सार्गठित प्रचार (propaganda) है। सर्याठित प्रचार का पहले अब शोला (decent) या, लेकिन प्रचार का अब अध कुछ व्यक्तियों एवं समूही हारा अच्य व्यक्तियों के विचारा एवं कार्यों को जपनी निश्चित पूर्व निर्माण करते हुए कहा है कि व्यक्तिय मां जन इच्छा का दमन या अन और नीति का प्रपानित है। मां वने या जन इच्छा का दमन या अन और नीति को प्रपतिव के विच एक ही मांग को उत्तर तरा एवं उसे सविधेष्ठ जानता हो अचार है। स्वाठित प्रचार के प्रवार के स्वर्ण का समन या अन और नीति को प्रचारित होट से सविधेष्ठ जानता है। स्वाठित प्रचार के प्रवार के स्वर्ण एक ही मांग को किस स्वर्ण करते हिए एक ही साम को किस स्वर्ण एक साम सार्ग स्वर्ण है। स्वरित उत्तर से इंटिंग साम स्वर्ण के समस एक मोनता एवं मांग स्वर्ण करता है, वह उसकी हिट्ट म सबसेष्ठ

^{13 &}quot;If public opinion is to have any meaning at all it should be intelligent intelligible and broad based"—E Asirvatham Political, Theory op cit p 488

हाता है एव जनता की उस नीति या माग को स्वीकार करन के लिए हर प्रकार स प्रमायित किया जाता है। लेकिन इस प्रकार जनता का जो मत बनता है वह लोकमत नहीं होता है।

भारत मे लोकमत

मारसवय ने उदारवादी लोकत'त्र के सिद्धाता को स्वीकार किया है। मौलिक अधिकारा एव विधि के सासन को व्यवस्था, यायपालिका की निष्पक्षता एव स्वत प्रता तथा ससदीय प्रणाली इसके प्रमाण है। सविधान की प्रस्तावना म समानता, स्वत प्रता एव प्रातुत्व प्रधान समान के निर्माण का उदबोधन तथा समानता एव दोषण के विरद्ध अधिकारी के द्वारा आधिक समानता का आक्ष्यातन दिया गया है। नीति निर्देश तथा का लक्ष्य सामाजिक कल्याण है। इन तथ्यो की पूर्ति के लिए लोकता प्रत्र पदित का वरण किया गया है। प्रश्न यह है कि क्या नारतीय मतदाताना म इन दिया को निर्मान की क्षमता है। प्रश्न यह है कि क्या नारतीय मतदाताना म इन दिया को निर्मान की क्षमता है। देश सावजनिक प्रस्ता पर पारतीय जनता स्वस्थ लोकनत का निर्मारण करन की क्षमता रखती है ?

करीव 150 वप तक विवेदी दासन काल म मारतीय जनता का दायण होता रहा । मिटिश काल म लोकमत के निर्माण का प्रका उठवा ही नहीं था । सावजनिक मामला म जुछ थोडे स ही व्यक्तिया को मल उपक करन क अधिकार प्राप्त थ । मता विकार वगगत, सीमित एव सम्भत्ति और साम्प्रदायिकता पर आधारित था । साव भीम वयस्क मताधिकार तो स्वत त्रता के परवात ही देश म प्रारम्भ हुआ है। प्रिटिन्नाल म काग्रेस दल एक मात्र प्रमुख राष्ट्रीय दल या और इसके अधिवना म दिय जाने वाले मापणा एव प्रस्तावा में मारतीय जनता के मत— लोकमत—मी अनिम्पिक्त होती थी । मुस्तिम साम्प्रदायिकता ने स्वस्य राष्ट्रीय लोकमत के निमाण म वाथा उत्पप्त को थी। मारतीय स्वत न्यता का जहाज अन्ततोगत्या साम्प्रदायिकता एव सकीप-वाद की पट्टान से थी। मारतीय स्वत निमाण म वाथा उत्पप्त की पट्टान से उपराकर दो माग्रा म वेट गया था। दण विमाणित हो गया।

यतमान स्वतात्र मारत म लोकमत थे निमाण एव अध्यक्षित य निए उपयुक्त यातावरण नहीं है अपितु अनेक वावाएँ हैं। देव जी अधिकार अवना अधिक्षित हैं। विगत 25 वर्षों म अध्यक प्रयास किय जान के वावजूद भी नवत 20 प्रतिरात नवता निक्षित हो समी है। साधारण भारतीय मायवादी एव परतावनारी हा उत्तित्त जनावित हो समी है। उत्तम उन नामिक चेता या अवाब है जा कि स्वस्थ तोकमत व गिमाण यो आधारित में रूप म नाम बरती है। 80 प्रतिशत जनता योवा म रहती है। आवागमन, याता-यात एव स नार की समृत्ति स्ववस्था ने अभाव म प्रत्यन योव एक दूसर त जुदा हुआ नहीं है। प्रामीण जनता अधिकारत जातिवाद न मधामक रोज प्रधीत्ति है। आज मा निवा म जिल्ला के प्रत्यन विवा के सम्वत्ति है। अपने मा निवा मंत्री के प्रमीत्ति है। अपने मा निवा मंत्री के प्रति है उत्ती है। अधिक नामिक स्वत्व है है उत्ती है। अधिक गर्मिंट में प्रामीण सेता म जातिवाद ना स्वानक क्षेत्र ने स्विप स्वप्ति स्वर्थ के स्वा विवास क्षेत्र ने स्वा निवास स्वा विवास स्वा विवास स्वा विवास स्वा विवास स्वा विवास स्वाप्त स्वा विवास स्वाप्त स्

77 }

महत्व है। निर्वाचना म विभिन्न राजनीतिक दलो के द्वारा अपने दलीय समीदवार गर चयन करते गमय सम्बन्धित निवाचन क्षेत्र म निवास करन वाला की जाति एवं सम्प्र-दाय विशेष को अनिवायत ध्यान म रखा जाता है। मुस्लिम या हरिजन प्रधान क्षेत्रा स अधिकारात प्रत्यक दल द्वारा मुस्लिम एव परिगणित जाति विशेष के मदस्य को ही प्रत्याची के रूप म चुना जाता है। सहरो क्षेत्रा म नी बहुधा यही देखा जाता है।

भारतीय शिक्षा-पद्धति भी दापपण है। विद्यालया एवं महाविद्यालयों म शिक्षा का मापदगढ एव स्तर निरातर गिरता जा रहा है। विद्यालय बत्यादन केंद्र या फाट-रिया यन गये हैं । चरित्र निर्माण, बुद्धिमानी, ईमानदारी, उत्तरदायिख आदि गुणा क विराम की ओर वाद्यित घ्यान नहीं दिया जाता है अपित पूगत उदासीनता पामी जाती है। शिक्षा प्रसार की गति घीमी है। विद्यालया म अनुपाननहीनता का सासाज्य है । गिक्षा जीवनापयामी नहीं है ।

नारतीय सामाजिक जीवन का एर सदा बहुता नागुर साम्प्रवायिकता है। मुस्लिम लीग का पुन उत्यान हो रहा है। इनस मारतीय ममाज ने हिन्दू एव मुस्लिम दो रोमा म बेंट जान रा मय है। अत बादरवकता यह है रि मुस्लिम सीत अमी साध्यन्यसिक सस्या पर प्रतियाध समा दिया जाय। स्पानीयता क्षत्रीयता एव मापा

वाद की सभीण प्रवत्तियाँ दश म अत्यधिक संविय है। देश म जामिक विषयता बढ़ रही है। धनी जिधक घंगी एवं निधन अधिर

निधन होता जा रहा है। मून्य-वृद्धि एवं मुद्रा-स्रीति न मामा य जनता यी पमर ही

सोड दी है।

ममापार-पन्ना का पूज स्वत त्रता प्राप्त है वर हु प्राय मनी गमापार-पत्र क्सी। विमी गृह, राजनीतिक क्स अपना भौषोषिक परिचार गमापी पा है।

सबस अधिक सावनीय तथ्य सावजीनक परित्र का ह्याम है। जीवन के प्रापक धेत्र म अनुसरणिय एव अवसरवाण्ति सहता व मूल म त वन गर्व है। अप्टा-पार का मंबन मामान्व है। ब्राप्ति अध्य हा मबा है। गरकारी मनीनरी पूरी तरह भारत है। बिना रिस्का दिव सिमी सरकार। काणाय में कोई काय नहीं कराया जा गरुता। प्रमानतं का प्रय समाप्त हो यदा है। प्रवर न नहर ती न तर नभी नम तारी अपनी नभा ना रुप्यमाव नरो है। यदि भारत न मोतत त अवस्त होता है ता वह - १ उनाः । वारण नहां हावा अधित यह उपन गरवासी वर्ष ৰণিয় গ श्वास के कारण हो असा । स्वतीविक पारिया ६ ह है। दान्यतह का राजनीति नव्यार ATT AL न्या सम राजनारि र बाद का म

ामार्थ स्थाप का *7 H AZ ! START TI

बदल राजनीति (Politics of Defection) में काँग्रेस के विमाजन के प्रचात कुछ कमी आयो है। परतु सामा य राजनीतिक जीवन नितकताहीन है। सावजनिक जीवन लोकमत | 897 में असत्य एव आचरणहीनता की प्रधानता है। चोरवाजारी, तस्करी, टैनस चोरी दुर्माग्यजनित वास्तविकताएँ बन गयी है । 14

मारत के लोकता त्रिक दत्ता को कायपद्धति पूणस्पेण लोकता त्रिक नहीं है। देश में एकल प्रवल दलीय पढ़ित है। काग्रेस (शासकीय) का देश में प्राथा य है। सबत एव सशक्त विरोधी दल का अमाव है। केंद्र म वैकल्पिक शासन का निमाण कर सकने वाले दल का पूण अमाव है।

उपरोक्त स्थित म स्वस्य लोकमत के निर्माण की जाशा मग मारीविका मात्र है। मारत वतमान म सकमण काल से गुजर रहा है। देश में शीझता से सामा-जिक एव आधिक परिवतन हो रहे हैं। पुराने जीवन मुख्यो एव मायताओं को अस्वी-कार किया जा रहा है पर तु जनका स्थान नवीन जीवन प्रत्य एवं मा यताएँ जतनी ही तेजी से नहीं ते रहे हैं। सामाजिक विषटन की प्रक्रिया सिक्रिय है। पुरानी सामा जिक यवस्या का स्थान नवीन व्यवस्था द्वारा तिया जाना स्वामाविक है । इस प्रकार के सामाजिक परिवतन के काल म नैराक्य को स्थित स्वामाविक होती है। लेकिन अधिकास म यह नराश्य यथास्यित बनाये रखने वालो के लिए मयानक होता है। राममनोहर लोहिया के अनुसार प्रत्येक मारतीय की दिनक आमदनी 31 पसे प्रति-दिन सं अधिक नहीं है। यह सोचनीय स्थिति है। ऐसी अवस्था म स्वस्थ लोकमत की चर्चा करना भी अभिशाप है। सिवधान प्रदत्त मीनिक अधिकार शो केस की दश-नीय वस्तु मात्र हैं। इन सबधानिक मौलिक अधिकारा का सामाय निधन भारतीय के लिए कोई महत्व नहीं है। विक्षित परन्तु वैरोजयार मारतीय नवयुवक के समक्ष व्यक्तिवादी अब व्यवस्था एवं लोकत न के नारा का कीई मूख नहीं है। आवश्यकता ब्याह्मवादा अप ब्यावस्था एव लाकता न कारा का कार पूर्व पहा हा आवस्यकता है कि इस सक्रमण काल म सीमण बिहीन समाज का निर्माण किया जाय एवं आवस्यकता ह कि इस सक्तम्य काल म स्थापम किहान समाय का गमाम क्रिया और एव जायम इरहा की मारछी प्रदान की जाय । इसके लिए यह व्यवस्थिक है कि काम का अधि पुरक्षा का गारण्या अवाग का जाव । इसका त्वर वह वाक्यक है कि काम का कार सभी मारतीया को प्रदान किया जाय और सम्मति के शक्तियां है। कार पाना गारधाला का कथान भावता थान थार प्रम्याच क बाध्यवाला दुवा का दिया जाय। उत्पादन के स्रोता वर समाज का निय नव होना चाहिए। राज्य प्रभाज ने अभिकृति के रूप में इस दायित्व का निवहि केरना चाहिए। अध्यापर ह प्रमाण १ जा गणता ४ २४ ७ ३० जामद्य जा लागात करणा भारत । अन्यापार कठोरतापुरक देमने किया जाना चाहिए। अन्य शासकीय कमचारिया एव व्यापारिय को सावजनिक शारीरिक दण्ड दिये जाने वाहिए।

इतनी निराधा की स्थिति में मी प्रत्यक मारतीय को उज्ज्वल मिनिय्य की बासा करनी चाहिए। वतमान भारत म लोकमत की जो मां बीसव्यक्ति होती है बाह्या करता चाह्य । वतमान भारत च जाकमत का चा जानच्याम एका व वह सामा य निर्वाचन काल में ही होती है पर तु वह भी पूरी स्पटना एव प्रबुद्धता स बहु लाभा भ ।नवाधन काल भ हा हाता ह ४६ तु वह भा ५६। १५५८०। एव अबुद्धवा ४ नहीं होतों । फिर मी एसिया एवं वाफीका के बनेक नवोदित स्वतंत्र देसों को तुलना म मारत में लोकमत की स्थिति अधिक सोचनीय नहीं हैं।

¹⁴ आपातकालीन घोषणा के परचात स्थिति म सुधार हुआ है।

दवाव (हित)-समूह [PRESSURE GROUPS]

आधूनिक सामाजिक जीवन विभिन्न जटिसताओ एव विषमताओ से पुक्त है। प्राप प्रत्येक देश से समान हित वाले व्यक्ति अपने को समूहों से सगठित करके अपने हिता एव स्वापों की रक्षा का प्रयत्न करते हैं। इ हे दबाव-समूद्ध (Pressure Groups) या हित समूह (Interest Groups) के समा वी जाती है। दवाव समूद्धों का महत्व विम प्रतिदिन वढ रहा है। एक समय इ हे स रेह की हम्टि से देखा जाता का महत्व विम प्रतिदिन वढ रहा है। एक समय इ हे स रेह की हम्टि से देखा जाता का सामा प्रजन एव राजनीति के गम्मीर विद्यार्थी दोगा ही इ ह उपहास की हम्टि या। सामा प्रजन एव राजनीति के गम्मीर विद्यार्थी दोगा ही इ ह उपहास की हम्टि या। सामा प्रजन एव राजनीति के गम्मीर विद्यार्थी दोगा ही इ ह उपहास की हम्टि या। सामा प्रजन एव प्रतिनिधि सासन की जड़ा को घीरे धीरे काट रही हो। 'लावी' अधुनिक लोकत क एव प्रतिनिधि सासन की जड़ा को घीरे धीरे काट रही हो। 'लावी' (Lobby) द्वाद्य का अथ दोष, प्रस्टाचार धोखाधड़ी आदि के समूह से सममा जाता (Lobby) द्वाद्य का अथ दोष, प्रस्टाचार धोखाधड़ी आदि के समूह से सममा जाता पा। 'दान द्वात समूही को सामाजिक मा पर्ता मिलने लगी और आज इ ह आददयक दुराई न मानकर स्वस्य सस्मा एव राजनीतिक जीवन का एक स्वस्य तत्व माना जाता है। आज से दो सी वप पूत्र समुक्त राज्य अमेरिका म बरनी (Verney) के अनुसार दवाव समूहा को आवश्यक नहीं समभाजाता या और काग्रेस कराये का हितो सम्ब धी भाग ही पर्याप्त माना जाता था। 'आज प्राप्त प्रस्त स्वस्यों का हितो सम्ब धी भाग ही पर्याप्त माना जाता था। 'आज प्राप्त हते अमेरिकी

¹ They were held upto scorn both by the muckrakers and by sane students of politics. They were the sinisters forces gnawing at the foundations of modern democracy of representative government and the word Lobby's supposedly comprehended a whole congeries of abuses corruption fraud and the like. — Carl J Freidrich Constitutional Government and Democracy, 1966 p. 460.

p 460 Verney, cited in M G Gupta Modern Government Theory and Practice 1966 p 206

विधायक किसी न किसी हित विशेष का अधिकृत प्रवत्ता होता है और उसका प्रति निधित्व करता है। दवान समूही द्वारा निधानमण्डलो को अपने हित म प्रमानित करने दवाव (हित) समूह | 899 का हर सम्मव प्रयत्न किया जाता है। दवाव समूह स्वय विधानमण्डल के पीछे लघु विधानमण्डल का रूप धारण कर चुके हैं। त्रों फाइनर ने इन दवाव सपूहों को अज्ञात साम्राज्य की सना दी है।

माईरन बीनर के अनुसार हित या दवाव समूह से अभिग्राय ऐव्हिक रूप से सगिवत ऐस समुदाय से हैं जो प्रचासकीय ढाने से बाहर रहकर शासकीय अधिकारियो के निर्वाचन, मनोनयन तथा सावजनिक नीति के निर्माण एव किया तथन की प्रमा वित करने का प्रयत्न करता है। " एम जो गुप्ता के अनुसार क्वाव या हित समूह एक ऐसा माध्यम है जिससे सामाय उद्देश्य बाले व्यक्तियो द्वारा सावजनिक मामता की कायविधि को प्रमावित करने का प्रयत्न किया जाता है। इस इस्टि से हर सामाजिक समूह जो औपचारिक रूप से शासन पर नियानण करने की कोश्विश किय विना ही प्रशासकीय एव विधायो दोनो प्रकार के राजनीतिक पदाधिकारिया के आचरण को प्रमावित करने का प्रयत्न करता है दबाद समूह या हित समूह कहनाता है। दबाद समूह त्रणक्षण राजनीतिक सगठन नहीं होते हैं। इनके द्वारा निर्वाचनों म प्रत्याधिया भार का मी लडा नहीं किया जाता और न इनका कोई राजनीतिक कायक्रम ही होता है। मासिस कतिहस के अनुसार 'दबाव समूह से जात्वय ऐते व्यक्तियों के समूह से हैं जो शासकीय कायकलापो या जनके विना ही राजनीतिक परिवतन लाने का प्रयत्न करते है। ऐसे दवाव समूहा को विधानमण्डल में राजनीतिक दल के रूप म मोई प्रति निधित्व प्राप्त नहीं होता।" दवाव समूह एव राजनीतिक दला म व तर अग्रवत है

³ According to Herman Finer Pressure groups are 'anonymous tuppire —Citted by M G Gupta Bid, p 206

By interest or pressure group we mean any voluntary organised by interest or pressure group we mean any voluntary organisms. group vorsine of the governmental structure which accompanies of governmental and a governmental structure. to innucince the nomination of appointment of governments of soften the adoption of public policy its administration of its administration of the control of personnel the adoption of public policy its administration of the adjudication. Myron Weiner cited by P. Saran Political Institution of the same political Institution of the sa hutons and Comparative Governments (In Hindi) 1971 p 725

Pressure groups may therefore be defined as a medium through which people with common inferests may endeavour to affect the which people with common interests may endeavour to ance; the course of public affairs. In this sense any social group which seeks to influence the behaviour of political officers both admit without affairs attenuation to pain formula. seess to minutesee the occasionary of pointest officers both administrative and legislative without attempting to gain formal nistrative and registative without attempting to gain formation control of government would be a pressure group "—M G Gupta Modern Governments Theory and Practice, 1967 pp 204 05 6 Cited by P Saran op cit p 725

(1) दवान समूहा की अपेक्षा राजनीतिन दलों के समरुन व्यापक होत हैं। उनके राजनीतिक कामक्रम होते हैं अबिक दवान समूहों का कोई राजनीतिक कामक्रम मही होता । दवान समूह का प्रधान सदय अपने हितों नी रक्षा करना होता है।

(2) राजनीतिक दलो भ शासन सत्ता को हस्तगत करन हेतु आपस म तीय प्रतिस्पर्धा होती रहती है जबकि दवाव समृह का उद्देश्य अपने हितो के अनुकृत विधियो

को पारित कराना एव विपरीत विधियों को पारित होने से रोकना है।

(3) राजनीतिक दलो की माति दवाव समूह निर्वाचनो मे भाग नहीं लेते हैं।

(4) दवान समूह विधानमण्डल के बाहर रहकर काय करते हैं। वे विधान मण्डल के अन्दर नहीं अधितु उसकी दीर्घा में सिक्य रहते हैं। विधानकों से सम्मक स्थापित करना और उन्ने अपने हितों की रक्षा के लिए काय करते हेतु प्रैरित करना

उनका प्रमुख काय है।

व्याव-समृद्दों का देश के सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहुलू से सम्बंध होता है। प्राय हुए उस देश में दवाब समृद्ध पाये जाते हैं जहा पर समुदायों के निर्माण की स्वत तता है। व्यापारिया, हिन्या खरसस्व्यक्ते, ख्रेमिका, कृषि कार्मों, चम्म व्यवसायों एव वृद्धों से सम्बंधित दवाव या दित समृद्ध एये जात है। ये हित-समृद्ध अपने हिता की रक्षाय वतनिक कमचारियों की नियुक्ति करते हैं। समुक्त राज्य अमेरिका में इन्हें लॉबोइस्ट (Lobbyist) कहा जाता है। शासकीय कमचारियों एव कार्यालयों से अपने हिता के रक्षाय इनके द्वारा निकट का सम्बंध रखा जाता है। दवाव समृद्ध सासक को अपने एक म प्रमावित करने के लिए सवस जनमत का निमाण करते हैं और रस पहुरेग होतु वे पर्याप्त कथा कथा करते हैं। जनता म अपने अतुकृत बातावरण बनान के लिए ये समाचार पना रेडियों, टेलीविजन एव लोक-सम्भव विशेषणा की सेवाए प्राप्त करते हैं। सक्ष्म म, स्वाव समृद्धा द्वारा हर सम्भव प्रचार एव साधन स अपने हित म जनमत तथार किया जाता है। शासन की प्रमासनीय एव विधायों नीतियों को वे प्रमावित करते हैं। रेस के विधायकों को अपने एक म करने का व हर प्रयत्न करते हैं स्वाय का अपने हित म प्रमावित करते हैं। रेस के विधायकों को अपने एक म करने का व हर प्रयत्न करते हैं स्वाया का अपने हित म प्रमावित करते हैं। है से के विधायकों को अपने एक म करने का व हर प्रयत्न करते हैं स्वाया सासकीय कमचारियां को अपने हित म प्रमावित करते हैं।

ब्रिटेन, सपुक्त राज्य अमेरिका बनाडा, फास जापान शादि रशो म विनिष्न द्याय या हित-मुद्द काय करते हैं। सपुक्त राज्य अमेरिका य दवाय समूह का प्रभाव शत्यिषक व्यापक है और इनकी सस्या सपुक्त राज्य म तीन लाख से भी अपिक है। दवाय समूह विभिन्न प्रकार के होते हैं। उदाहरण वे तिए, छोटे व बढ़े, प्राक्तिसाती

एव कमजोर, स्पामी एव अस्थामी आधिक एव व्यावसामिक आदि।

दवाव-समूह के निर'तर बढ़ते हुए महत्व के लिए उत्तरदायी तत्व

प्रत्यन देशे मं दबाव-समूहां क महत्व म वृद्धि क लिए पृथक तत्व उत्तरदायी हैं। परन्तु पुद्ध सामाय तत्व प्राय प्रत्यक देग म सम्रिय हैं। यमेरिका, दिटन, ननाडा एव आस्ट्रेलिया म प्राय प्रत्यक दबाब या हित-समूह राजनीतिय दला को प्रभावित करता है। फास जैसे देश म जहा वहदलीय पद्धति है, विभिन्न दवाव समूह अपने को विभिन्न दलों से सम्बद्ध कर लेते हैं। अत फास में विभिन्न दल विभिन्न हिंत-समूहा से अमिन्न रूप में सम्बन्धित हैं। फ़ासीसी दलो के द्वारा इन वर्गीय एव विशिष्ट हितों को सामा य राष्ट्रीय हितों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संयुक्त राज्य अमे-रिका म दवाद समुहो के विकास के लिए प्रधान रूप से देश का विशाल आकार, राजनीतिक दलो का अस्पष्ट कायरूम एव ससदीय जासन व्यवस्था का अमाव उत्तर दायी है। इसके अतिरिक्त शक्ति पृथक्करण के सिद्धा ता पर आधारित अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अ तगत विधि निर्माण का दायित्व कायपालिका-राष्ट्रपति-के हाथों मे न होकर काग्रेसजनो के हाथा म केन्द्रित है। फलस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका म ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गयी कि समान व्यवसाय या उद्योगों से सम्बर्ध घत व्यक्ति अपने हितों के रक्षाय एक समुद्र में सगठित होने लगे और अपने स्वार्थों के अनुकल विधियो के निर्माण, विरोधी विधियों के निर्माण को रोकने तथा विधायकों को प्रमावित करने के प्रयत्न करने लगे। ऐसी ही परिस्थिति म 1823 ई में संयुक्त राज्य अमेरिका मे पोक वेरल विधान (Pork barrel legislation) का विकास हुआ था। समुक्त राज्य अमेरिका म जब किसी विशेष समूह या क्षेत्र को राजनीतिक उद्देश्य के लिए शासकीय अनुदान या धन प्रदान किया जाता है तो सम्ब धत विधेयक को विरोधियो द्वारा पोक बेरल विधेयक की सज्ञा दी जाती थी। 1823 ई मे नदियो एव व दरगाहो के लिए धन-राद्यि स्वीकृत करने वाला ऐसा प्रथम विधेयक पारित किया गया था । उस समय की तुलना म दबाब या हित समृहा की सख्या मे असाधारण रूप से बद्धि हुई है और अब तो संयुक्त राज्य अमेरिका म दबाव समहो को सावजनिक मा यता प्राप्त हो गयी है।

ग्रेट ब्रिटेन म 19वी सवी के मुचार आ दोलना के परिणामस्वरूप दबाव समूहा का विकास हुआ है। वे थम, कॉब्डन एव मिल का इस प्रकार के हित समूहा से सम्बाध था। इस समय महाद्वीपीय देखों म निजी समूहा का भी अस्तित्व था। लोक-कत्याणकारी राज्य की धारणा क विकास तथा आर्थिक जीवन म राज्य के बढते हुए हस्तक्षेप के कारण दबाव समूहा की गतिविधियों में असाधारण वृद्धि हुई है। राज्य के बढते हुए इस्तक्षेप के कारण दबाव समूहा की गतिविधियों में असाधारण वृद्धि हुई है। राज्य के बढते हुए स्तियं के सम्मावन के लिए हर राज्य में बढी सख्या में कमचारियों की निगुक्त किया जाता है। शासन विमिन्न उद्योग का, यहा तक कि निजी क्षेत्र के उद्योगा की भी आर्थिक अपुदान (subsidies) प्रदान करता है। यही नहीं, राज्य व्यापार, उद्योग एव कृषि का नियमन भी करता है। इस सबके फतस्वरूप व्यक्ति अधिकाधिक सासन पर निमय रहन लग है और उनम यह धारणा प्रय कर पयी है कि यदि वे समय रहते हुए ठीक दम स प्रशासन पर स्वान म सफल हो जाते हैं तो उद्द अपनी किसी शृदि या दाय के लिए अनावस्थक रूप से कोई हानि नहीं होगी। प्रत्यक्त

- (1) दवाय-समूहा को अपक्षा राजनीतिव दक्षा के सगठन व्यापक होत हैं। उनके राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं जबकि दबाव ममूहो का कोई राजनीतिक वायकम नहीं होता। दवाय समृह का प्रधान सक्ष्य अपने हितो की रक्षा करना होता है।
- (2) राजनीतिक दला म शासन सत्ता को इस्तगत करन हेतु आपस म तीय प्रतिस्पर्या होती रहती है जबकि दबाब समूह का उद्देश अपने हितो के अनुकूत विधिया को पारित कराना एव विषरीत विधियो को पारित होने से रोकना है।
 - (3) राजनीतिक दलो की मौति दवाव समृह निर्वाचना म माग नही लेते हैं।
- (4) दवाव समूह विधानमण्डल के वाहर रहुकर काय करते हैं। वे विधान-मण्डल के अन्दर नहीं अभिनु उसकी दीर्घों में सनिय रहते हैं। विधायकों में सम्मक स्थापित करना और उन्हें अपने हितों की रक्षा के लिए काय करा हेतु प्रेरित करना उनका प्रमुख काय है।

वाब समुहों का देश के सामाजिक जीवन के अरवेक पहुन् से सम्बंध होता है। प्राय हुट उस देश में दबाव समूह पाय जाते हैं जहीं पर सपुत्रायों में निर्माण की स्वत त्रता है। व्यापादियों, हिनमा अल्यस्वयाने, हैं जहीं पर सपुत्रायों में निर्माण की स्वत त्रता है। व्यापादियों, हिनमा अल्यस्वयाने, ह्रामिकों हृपि फार्मों, प्रमु, व्यवसाया एव वृद्धा स सम्बंधित बवाव या दित-समूह पाये जाते हैं। यहुक राज्य अमेनिका म इ ह लॉबीइस्ट (Lobbyist) कहा जाता है। बातकीय कमचारियों एव कार्यालयों से अपने हितों के रक्षाय इनके हारा निकट का सम्बंध तथा जाता है। दबाव सपूर्व शासन का अपने पक्ष म प्रमावित करने का लिए सवक जनमत का निर्माण करते हैं और इस उद्देश हेतु वे पर्योग्त का क्या करते हैं। जनता से अपने अनुकृत बातावरण बनाने के लिए सवक सम्वार्थ करने के नुकृत बातावरण बनाने के लिए सवक समावर-पन्नों, रेडियों, टेलीविजन एवं लोक-सम्पन्न विशेषकों की सेवाए प्राप्त करते हैं। सक्षेत्र में, दबाव समूहा द्वारा हुर सम्भव प्रचार एवं साधन से अपने हित में अनमत तथार किमा जाता है। बातव की प्रवासकीय एवं विषयों नीतियों को वे प्रमावित करते हैं। वे के विधायकों को अपने पक्ष म करने का व हर प्रयत्न करते हैं स्वार धाराविक करते हैं।

त्रिटन, समुक्त राज्य अमेरिना, कनाडा, फास आपान बादि देशो म विधिन्न याव या हित समूह नाय करते हैं। त्रमुक्त राज्य अमेरिका में स्वाव समूह का प्रमाव अत्यधिक व्यापन हैं और इनकी सच्या समुक्त राज्य में तीन सास्त्र से मी अधिन हैं। दयाव समूह विभिन्न प्रकार के होते हैं। उदाहरण ने लिए, छोटे य बड़े, चिक्ताशी एवं कमजीर, स्थामी एवं अस्थामी आधिक एवं व्यावसायिक बादि।

दबाव-समूह के निर तर बढते हुए महत्व के लिए उत्तरदायी तत्व

प्रत्येण देश मे दबाब-समूहो ने महत्व मे बृद्धि के लिए पृथक तत्व उत्तरदायों हैं। परत्तु कुछ सामाय तत्व प्राय प्रत्येक देश में सिक्रय हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, पनाडा एव आस्ट्रेलिया मे प्राय प्रत्येक दबाब या हित-समूह राजनीतिक दत्तो को प्रमावित करता है। फास जैसे देश मे जहा बहुदलीय पद्धति है, विभिन्न दवाव ममूह अपने को विभिन्न दलों से सम्बद्ध कर लेते हैं। अत फाम में विभिन्न दल विभिन्न हिन समूहो से अभिन्न रूप में सम्बन्धित हैं। फासीसी दला के द्वारा इन वर्गीय एवं विशिष्ट हितो को सामा य राष्ट्रीय हितो के रूप मे प्रस्तुत किया जाता है। मयुक्त राज्य अमे-रिका म दबाव समुहो के विकास ने लिए प्रधान रूप से देश का विशाल आकार, राजनीतिक दलो का अस्पष्ट कामकम एव ससदीय शामन व्यवस्था का अमाव उत्तर दायी है। इसके अतिरिक्त शक्ति पृथक्व रण के मिद्धा तो पर आधारित अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अत्तगत विधि-निर्माण का दायित्व कायपालिका---राष्ट्रपति--के हाथो मे न होकर काग्रेसजनो के हाथों म कंद्रित है। फलस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसी परिस्थितिया उत्पन्न हो गयी कि समान व्यवसाय वा उद्योगा से सम्बन्धिन व्यक्ति अपने हिना के रक्षाथ एक समूह म सगठित होने लगे और अपन म्वायों क अनुकृत विधियो क निमाण, विराधी विधिया के निर्माण को रोकने तथा विधायको का प्रमावित करन के प्रयत्न करन लगे। एसी ही परिस्थिति में 1823 ई म समुक्त राज्य अमेरिका म पोक-नेरल विभान (Pork barrel legislation) का विकास हवा या । मयुक्त राज्य अमेरिका म जब निसी विशेष समृह या क्षेत्र को राजनीतिक उद्देश्य के लिए गासकीय अनुवान या धन प्रवान किया जाता है तो सम्बन्धित विधेयक को विरोधियो द्वारा पोक-बेरल विभेयक की सजा दी जाती थी। 1823 ई म नदिया एव वादरगाहा के लिए धन-राशि म्बीकृत करने वाला ऐसा प्रथम विधेयक पारित किया गया था । उस समय की तुलना में दबाब या हिन समृही की सच्या म असाधारण रूप म वृद्धि हुई है और अब तो समुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समुहो की सावजनिक मा यता प्राप्त हो गयी है।

प्रद विदेल म 19थी सदी के सुधार आ दोलना के परिणायस्वरूप दवाव-समूहा का विकास हुआ है। वे पम, कोंडवन एव मिल का इम प्रकार के हिल समूहों से सम्बन्ध वा । हुस समय महाडोपीय देशों म निजी समूहों का भी अस्तित्व था। लोक-कल्याणकारी राज्य की धारणा के विकाम तथा आधिक जीवन से राज्य के धवत हुए स्तर्भेष के कारण दवाव समूहों की मतिविधिया म अमाधारण बृद्धि हुई है। राज्य के बढते हुए दामित्व के सम्पादन के निल् हुई राज्य म वढी सच्या में कमचारियों की निगुक्त की गयी है। आज राज्य द्वारा सबसे अधिक सस्या म कमचारियों को निगुक्त किया जाता है। शासन विभिन्न उद्योगा का, यहाँ तक कि निजी क्षेत्र के उद्यागा की भी आर्थिक कनुदाना (subsidies) प्रदान करता है। सही नहीं, राज्य व्यापार, उद्योग एव स्थाप का नियमन भी करता है। इस सबके फलस्वक्रम व्यक्ति अधिकाधिक सासन पर निमर रहने वर्ष है और उनम यह धारणा घर कर वर्षों है तो यह अभम पहले हुए ठीक ढण ये प्रशासन पर दवाव वालन म मफल हो जाते हैं तो उन्ह अपनी किसी बृद्धि या दाध के लिए अनावस्थक रूप से कोई हानि नहीं होगी। प्रत्येक अपनी किसी बृद्धि या दाध के लिए अनावस्थक रूप से कोई हानि नहीं होगी। प्रत्येक

व्यक्ति राज्य कं विपरीत प्रमान एन हस्तक्षेप सं अपन हिता की रक्षा कं लिए हर सम्मव प्रयत्न करता है।

एक अप तच्य बडा महत्वपूण है । जिस अनुपात में शासन की शक्तियों म बहि हुई है उसी अनुपात म ससद की शक्ति का ह्यास हजा है। राजनीतिक दला के विशेष हिता (interests) सं सम्बद्ध हो जान पर विधानमण्डल भी उन्हीं विशेष हिता के हाथा में खेलने लगता है और विधायका पर इन विश्लेष हितों का इतना प्रभाव वढ जाता है कि वे उनकी उपेक्षा करन स असफल हो जाते हैं। फलस्वरूप विधानमण्डल के प्रतिनिधि स्वरूप मे अन्तर पड जाता है। इसके अतिरिक्त दलीय अनुशासन भी कठार हा गया है और उसी अनुपात म प्रतिनिधि समा के व्यक्तिगत सदस्यों के सम्मान का स्तर भी गिरता गया है। बिटिश कॉम स समा म होने वाले वाद विवादों एव मतदान में अब जनता को पहले की माति रुचि नहीं रही है। आज शासन एव विशेष हिता के मध्य होन वाले विचार विमय के परिणामों म जनता की काम म समा के मतदाना एवं निषया संअधिक रुचि होती है। इसी अथ मं ददाव समूहा की विधानमण्डल के पीछे एक अय विधानमण्डल की सना दी जाती है। दबाव-समुहा को आधुनिक लोकत तो म उपलब्ध वैज्ञानिक प्रचार-साधनो की उपलब्धि के फलस्वरूप विशेष स्थिति प्राप्त हो गयी है। वे झासन के निमाता (King makers) यन गये हैं। विशेष स्थितिया में उनके प्रमाव म असाधारण विद्व हो जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका म तो इ ह ततीय सदन (Third House) एव सहायक शासन (Assistant Government) कहा जाता है।

प्रो फाइनर के अनुमार जब राजनीतिक दला क सिद्धा त एव सगठन म शिय-लता एव कमजोरी आ जाती है तब दबाव समूहा को फतने फूलने क्या जबसर प्राप्त हो। जाता है और वे अधिक शिक्षाशीलों हो जाते हैं। जहा दबाव समूह शिक्षाशीलों होते हैं बहाँ पर राजनीतिक दल कमजोर होते हैं और जहार गजनीतिक दल शिक्षाशीलों होते हैं। दबाव ममूह कमजोर हो जायेंगे। किंकिन हर्सन फाइनर का यह मत पूणक्पण सप्त नहीं है। ग्रेट ब्रिटन में राजनीतिक दल सिद्धा त एव सगठन की हृश्य स पर्मान्त शिक्ष शाती है, यहा तक कि समुक्त राज्य अमरिका के राजनीतिक दला म सिद्धा त एव सगठन म वह देवता नहीं हैं जो ग्रेट ब्रिटेन के राजनीतिक दला म पायी जाती है। वया इसका यह अथ है कि समुक्त राज्य अमरिका की ब्रोखा ग्रेट विटेन के दबाव-समूह कम शिक्षाशी हैं हैं ब्रिटेन के विष्य समुह के अथकाकृत कम प्रमावशाली हों ने के अप कारण है। ग्रेट ब्रिटेन के विष्य में हितो एव सम्बर्धिय व्यावशायिक सस्वाओं

⁷ Finer op est pp 458 and 460

⁸ Finer Governments of Greater European Powers, p 34, cited by M G Gupta op cit, p 207

तया हित-समुहा का सम्बन्धित विधिया के निर्माण को स्व हित म प्रमानित करने के लिए अय तरीके उपलब्ध हैं। ब्रिटन म राजनीतिक दला के माध्यम से विभिन देवाव-समह अपन पक्ष म सम्बन्धित विधान को प्रभावित बरन म सफल होते हैं क्योंकि इन राजनीतिक दला म विज्ञिन हित समूह होत है। जत विमिन हित समूह दल के भीतर से या दलीय स्तर पर विधान (legislation) को अपने पक्ष म प्रमावित करने म सफल होते हैं। विधि निर्माण के दौरान म विमिन्न म-त्रालया की भी औपवारिक रूप से सम्बर्धित पक्षा द्वारा अपना मत प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार किसी प्रस्तावित विधि में अन्तिम रूप में पारित होन तक सम्बन्धित पक्षों या हित-समुहों को अपने पक्ष में प्रभावित करन का अवसर प्राप्त हो जाता है। अत स्पष्ट है कि मन्त्रा सय स्तर पर भी विधान को प्रचावित किया जा सकता है। सत्य तो यह है कि ग्रेट निटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की डिटलीय पद्धति द्वारा विभिन्त हण्टिकीणा तथा अनक प्रकार की समस्याजा का निश्चित रूप स प्रतिनिधित्व सम्मव नही होता है। दवाव-समुहो द्वारा अध्यक्षात्मक दासन प्रवासी म सवधा भिन प्रकार की भूमिका निमामी जाती है जबकि ससदीय देशा म उनकी स्थिति मिन हाती है । शक्ति पृथ-क्करण पर आधारित जन्यक्षात्मक धासन प्रवाली (यथा—संयुक्त राज्य अमेरिका) मे कायपालिका द्वारा विधि निर्माण के सन्दम म प्रधान भूमिका नहीं निमायी जाती है। सभी विधि विधायको द्वारा प्रस्तावित की जाती हैं । समुक्त राज्य अमेरिका म विधि निर्माण के क्षेत्र में राष्ट्रपति की अपक्षा कांग्रेस की अधिक अवसर प्राप्त हैं। अत बहाँ कप्रिस के सदस्यों (कप्रिसजन) एवं सम्बर्धिय समितियों के सदस्यों से सम्पन स्पापित करना एव उ ह अपन पक्ष म प्रमावित करना बावश्यक है। इसलिए समुक्त राज्य अमरिका म सम्बाधित दवाव समुद्रा द्वारा कार्यसञ्जनो को प्रमादित करने वाले कमन्तरियो (Lobbyisis) की नियुक्ति की जाती है । य सीनेटरी एव प्रतिनिधि सदन के सदस्या तथा समितिया के सदस्यों का समयन प्राप्त करने के लिए उन्हें घूस देत हैं और हर प्रकार के अंदर एवं अवाद्यनीय साधना को अपनाने म नहीं हिचनते हैं। ससदोय व्यवस्था म विधि निर्माण पर शासन (मि नमण्डल) का एकाधिकार होता है। मित्रमण्डल के द्वारा 85 स 90 प्रतिशत तक विधेयक संसद में स्वीकृति हेत् प्रस्तृत किये जाते हैं। दलीय बहुमत क कारण उनका पारित हो जाना स्वामाविक है। व्यक्तिगत सदस्या द्वारा प्रस्तावित विषेयक महित्रमण्डल के समयन से ही पारित ही सकते हैं । स्पष्ट है ससदीय व्यवस्था प्रधान देशा में किसी समूह विरोप को अपने हित म वाद्यित विधि के निर्माण हेत् सम्बाधित म ती. मात्रालय एवं मित्रमण्डल की प्रमा वित करना आवश्यक है। ससदीय व्यवस्था मे दलीय स्तर पर दलीय दवाव द्वारा भी वाहित विधि का निर्माण करा सकता सम्भव होता है। यदि विसी मंत्री द्वारा कोई विभेयक किसी रूप में विधानमण्डल में प्रस्तुत किया जाता है तो इसका यह सहज अप है कि उस रूप में उस विधेयक को पारित करने का निश्चय मिन्त्रमण्डल ने

904 | आधुनिक शासनत व

यदि उसम परिवतन या सदीधन कराना है तो वह विधानमण्डल के स्तर पर नहां अपितु मि त्रमण्डलीय स्तर पर ही सम्मय है। अत सिद्धात एव समझन पी होन्ट से राजनीतिक दला नी पिक्त या प्रक्तिहीनता का दबाव समूहो की प्रक्ति या प्रक्तिनता स कोई सम्बाध नहीं है।

समुक्त राज्य अमेरिका एक वृहद् दर्दा है। वहाँ के क्षेत्रीय हित निम्न निम्न हैं। विमिन्न क्षेत्री स सम्बाधित हित अपने स्वायों के अनुरूप स्वीय मीति को प्रमावित करने का हर सम्मय प्रयत्न करते हैं। इससे मी समुक्त राज्य अमरिका म दवाव न्याह्म की सस्या एय प्रमाय म असाधारण वृद्धि हुई है। न्निटन म सयुक्त राज्य अमरिका की सीति दवाव नमूह्य हारा विधानमण्डत की सीचे प्रमावित नहीं निया जाता है। मास म विटेन की अपेक्षा दवाव समूह अधिय खिल्ह्याती हैं पर जु उतने ही वे अनु करायायी मी हैं। इसका प्रधान कारण यह है कि का स ससदीय व्यवस्था होते हुए भी बहुदसीय पद्मित के कारण सिंप निमाण म कायपालित की भूमिका प्रमुख नहीं है। फेन विधानमण्डल —असेम्बली—मि त्रमण्डल की अपेक्षा अधिक सिक्ताती है । के विधानमण्डल —असेम्बली—मि त्रमण्डल की अपेक्षा अधिक सिक्ताती है अने विधानमण्डल —असेम्बली—मि त्रमण्डल की अपेक्षा अधिक सिक्ताती है

दबाव-समूहो के काय एव कार्यपढित

वबाय समूहो के काय

ववाय समुद्दा के कांध

दवाय समुद्दा के कांध

दवाय समुद्दा का क्या काय है ? दूसरे दाब्दों में, वे देश की राजनीतिक प्रक्रिय
का किस प्रकार प्रमावित करते है ? प्रमावित करने के उनके साधन एव पद्धित क्या है ?

गाधुनिक जटिल समाज में ब्यक्ति अकेसे अपने हिता है रिकामही कर सकता है, अत
विभिन्न प्रकार के समूद्दों, सगठना का निर्माण हुआ है। उवाहरण के लिए, प्रमिक्ता
द्वारा अपनी मार्गे पूरी करने के सिए जव सुट्ट प्रमिक सगठन का निर्माण किया गया
दो उद्योगपितयों ने भी मितकर अपनी रक्षा के प्रयत्न करना प्रारम्म कर दिया।
अत यह स्पष्ट है कि आधुनिक औद्योगिक या विकास मुख समाज में ब्याप्त प्रति
स्पर्धा एव विदिलता के कारण विभिन्न समुद्दों का उदय हुआ है। एक हित-समूद्द म
एक ही हित वाले ब्यक्ति द्यामित होते हैं। समूद्द जीवित रहने के लिए आवस्पन होत
हैं। अत आधुनिक काल में दवाद या हित समूद्द अनिवाय ही नहीं, अपितु वाद्यनीय
होते हैं।

दबाव समुहो के सामा यत निम्न काय है

(1) अपने सदस्यों के हितो—आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सास्कृतिक (जिं ह प्राप्त करने के लिए हित समूह का निर्माण किया मथा है)—को प्राप्त करने का प्रयस्त करना। राज्य के सकारास्थक स्वरूप एवं नियोजन के कारण उसकी सिक्त्यों मं असाधारण बढि हुई है। सामन की सत्ता रूपी तलवार स हित समूह अपन सदस्या की रक्षा के लिए बाल का काय करते हैं।

(2) आधुनिक समाज मे हितो की विभिनता एव अधिकता पायी जाती है।

अनेक प्रकार के हित समाज मे पायं जाते हैं। हित बीम य के फलस्वरूप मनुष्यं के स्वास्तित्व के विकास के लिए सामाजिक जीवन म विभिन्न क्षेत्र खुल जाते हैं। सामाजिक जीवन मे किसी एक हित की प्रधानता मी नहीं होती और न उसका एक धिकार ही होता है। दवाव समूहों के द्वारा हितों की विविधता एवं उत्तम प्रतिस्पर्धा को सहल ही प्रथय प्रदान किया जाता है जिसके फलस्वरूप वे अप्रथक्ष रूप में सामा य मत (Con sensus) के निर्माण म सहायक होते हैं। लोकत य मे विचार विमश्च एवं वाद विवाद की स्वत त्रता एक अनिवायता होती हैं अ यथा उसे लोकत न कहना ही गलत है। यदि किसी समाज मे मतमेद एवं विचार विमश्च को गुलाइस नहीं है तो वह सर्वाधिकारी समाज (Totalitanian Society) है। ऐसा समाज गितहीन होता है तथा उसम मानव व्यक्तित्व के कुण्टित होने की हर सम्मावना होती है। लोकत न म मतमेद एवं सत्त विम्य स्वामाविक है। दवाव समूहों के द्वारा यह मतमेद एवं सत वीमा य अभिन्यस्त होते रहते हैं। दवाव समूहा म पारस्परिक प्रतिस्थर्ध मी होती रहते हैं लेकिन वक्त गान स्वामाविक है। दवाव समूहा म पारस्परिक प्रतिस्थर्ध मी होती रहते हैं लेकिन वक्त ग्री स्थल प्रतिस्थर्ध आत्मधाती नहीं होती। य एक दूसरे का केवल उस सीमा तक ही विरोध करते हैं जहाँ तक कि उनके हितों में स्थण होता है। होता है।

(3) दबाब समूह लोकत न में बाधक नहीं है, अपितु वे लोकत न को ब्यवस्था म सहायक होते हैं। अत उन्हें लोकत न का पर्यायवाची कहने म कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वतमान समाज में ब्यक्ति व समूहों के हिता में कोई विरोध नहीं हैं। लोकत त्रीय समाज में ब्यक्तियों को पर्याप्त स्वत नता प्राप्त है, विभिन्न विकल्प उप-सन्ध होते हैं, कोई दबाब एवं धोस का बातावरण नहीं होता। समाज के विभिन्न हित समूहा द्वारा खासन की अनुचित नीतियों का विरोध समाज के असरिटत जना

की तरफ से किया जाता है।

(4) निर्वाचन काल म दवाव समूहो द्वारा लाक्ता निक व्यवस्था को जीवित एव जागृत रखा जाता है। वे इस काल म कायपालिका की निरकुशता पर अवरोधक रूप म काय करते हैं। अपने हिता की रक्षाय अपने विविद्ध तान तथा प्रमापित करने की असाधारण कला का उत्साहपूत्रक प्रयोग करके सदन एव समिति स्तर पर वे विधि निर्माण की प्रमापित करते हैं

(5) दवान समूह सावजिनक हित की अपेक्षा अपने व्यक्तिगत ममूह हित में अधिक सिक्य होने है, परन्तु दवान समूहों के द्वारा सम्बिधत विषयों म निशेषकर तक-नीकी एवं विविद्ध सामलों में जो आकडे और तथ्य उपस्थित किये जात हैं वे प्रशासका

एव विधायनो के लिए विधि-निर्माण म पयाप्त सहायक होते हैं।

(6) प्रतिनिधित्व के सम्ब घ म भी दबाव-समूहा द्वारा महत्वपूर्ण नूमिका निमाई जाती है। प्राय प्रत्यक देश म प्रतिनिधिया का निर्वाचन क्षेत्रीय आ पर गर होता है लेकिन मतदाता का हित केवल एक क्षेत्र स ही सम्ब धित नहीं उससे जनेक व्यावसायिक सामाजिक एवं अय हित होते हैं। स्मर्ी यदि उसम परिवतन या सद्योधन कराना है तो वह विधानमण्डल के स्तर पर नहीं अपितु मिन्नमण्डलीय स्तर पर ही सम्मव है। अत सिद्धात एव सगठन की होट से राजनीतिक दला की शक्ति या शक्तिहीनता का दवाव समूहा की शक्ति या शक्तिहीनता से कोई सम्बाध नहीं है।

समुक्त राज्य अमेरिका एन नृहद् देश है। बहाँ के क्षेत्रीय हित निम्न निम्न हैं। विसिन्न होगा से सम्योपत हित अपने स्वायों के अनुरूप समीय नीति को प्रमावित फरने हो हर सम्मव प्रमत् करते हैं। इससे नी समुक्त राज्य अमेरिका म दवाव-प्रमृहीं की सस्या एव प्रमाव म असाधारण बिद्ध हुई है। ग्रिटेन म समुक्त राज्य अमेरिका की माति दवाव-प्रमृहों हारा विधानमण्डल को सीधे प्रमावित नहीं निया जाता है। फास म ग्रिटेन की अपेक्षा दवाव समूह अधिक खिक्काली हैं पर चु उतने ही वे अमु सरदायों नी हैं। इसका प्रधान कारण यह है कि कास म सबदीय व्यवस्था होते हुए मो वहदसीय पद्धति के कारण विधि निर्माण म कायपालिका नी भूमिका प्रमुख नहीं है। फेंच विधानमण्डल—असेव्यवती—मिनण्डल की अपेक्षा अधिक शिक्काली हैं। भेर विधानमण्डल—असेव्यवती—मिनण्डल की अपेक्षा अधिक शिक्काली हैं।

दवाव-समूहो के कार्य एव कार्यपद्धति

दथाय समुहो के काय

विवाद समुद्दा के काय
द्वाद समुद्दा के काय
दवाद समुद्दा का नया काय है ? दूसरे धव्यो से, वे देख की राजनीतिक प्रियम
को किस प्रकार प्रमाबित करते है ? प्रमावित करने के उनके साधन एव पद्धित क्या है ?
आधुनिक जटिल समाज मे व्यक्ति अकेले अपने हिंदो है ! उदाहरण के रिक्त है , अद विभिन्न प्रकार के समूद्दो, सगठनों का निर्माण हुआ है ! उदाहरण के लिए अमिका ब्रारा अपनी मार्ग पूरी करने के लिए जब सुद्ध अमिक सगठन का निर्माण किया माया तो उद्योगपितयों न भी मित्रकर अपनी रक्षा के प्रयत्न करना प्रारम्भ कर दिया ! अत यह स्पष्ट है कि आधुनिक औदोगिक या विकासो मुख समाज मे व्याप्त प्रति स्वधा एव जटिलता के कारण विभिन्न समूद्दों का उदय हुआ है । एक हित-समूद्द भ एक ही हित बाले व्यक्ति सामिल होते हैं । समूद्द औदित रहने के लिए वाबस्यक होते हैं । अत आधुनिक काल म दवाव या हित समूद्द अमिनाय हो नही, अपितु वाछनीय होते हैं ।

दबाव समूहा के सामा यत निम्न काय हैं

- (1) अपने सदस्यों के हितो—बार्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, मास्कृतिक (जिंह प्राप्त करने के लिए हित समूह का निर्माण किया गया है)—को प्राप्त करने का प्रयस्त करना। राज्य के सकारात्मक स्वस्य एवं नियोजन के कारण उसकी शक्तियों में असाधारण वृद्धि हुई है। शासन की सत्ता रूपी तलवार सं हित समूह अपने सदस्यों की रक्षा क लिए दाल का काय करते है।
 - (2) आधुनिक समाज मे हिंवो की विभिन्ता एव अधिकता पापी जाती है।

अनेक प्रकार के हित समाज में पाय जाते हैं। हित वैधि य के फलस्वरूप मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए सामाजिक जीवन म विधिन संश्व खुल जाते हैं। सामाजिक जीवन म किसी एक हित की प्रधानता भी नहीं होती और न उसका एक पिकार ही होता है। दवाब समृहा के हारा हितों की विविध्वा एव उनमें प्रतिस्पर्ध को सहज ही प्रथा प्रवान किया जाता है जिसके फलस्वरूप वे अप्रयक्ष क्या सामाय मत (Consensus) के निर्माण में सहायक होते हैं। लोकत के में विचार विमय एव वाद विवाद की स्वत प्रता एक अनिवायता होती है अयया जसे लोकत के कहना ही गलत है। यदि किसी समाज य मतभेद एव विचार विमय की युवाइश नहीं है तो वह सर्वाधि कारी समाज (Totalhtanan Society) है। ऐसा समाज गतिहीन होता है तया उसम मानव व्यक्तित्व के कुण्ठित होने के हर सम्मावना होती है। लोकत के में मतभेद एव मत विभा य स्वाम-वस्त होते रहते हैं। दवाब समृहों के हारा यह मतभेद एव मत विभा य स्वाम-वस्त होते रहते हैं। दवाब समृहों में पारस्परिक प्रतिस्पर्ध में होती रहती है लेकिन जनकी यह प्रतिस्पर्ध कारमध्यती नहीं होती। वे एक दूसरे का केवल उस सीमा तक ही विरोध करते हैं जहां ति कि ति के कि उनके हिता में सप्य होता है।

(3) दबाब समृह लोकतात्र में बाधक नहीं है अपितु वे लोकतात्र की व्यवस्था म सहायक होते हैं। अत उन्हें लोकतात्र का पर्यायवाची नहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वतमान समाज में व्यक्ति व समृहों के हिता म कोई विरोध नहीं है! लोकत तीय समाज में व्यक्तिया को पर्यान्त स्वत तता प्राप्त है, विभिन विकल्प उप लब्ध होते हैं, कोई दबाव एवं धीस का बातावरण नहीं होता। समाज के विभिन्न हित्त समूहों द्वारा पासन की अनुचित नीतियों का विरोध समाज के असगिठित जना की तरफ से किया जाता है।

(4) निर्वाचन-काल म दबाव समूहो द्वारा लोकतानिक व्यवस्था को जीवित एव जागत रखा जाता है। वे इस काल म कायपालिका की निरकुशतापर अवरोधक रूप में काय करते हैं। वपने हिता की रक्षाय अपने विविद्ध झागतथा प्रमालित करने की असाधारण कता का उत्साहभूवक प्रयोग करके सदन एव ममिति स्तर पर वे विधि-निर्माण की प्रमावित करते हैं

(5) दबाब समूह सावजिनक हित की अपेक्षा अपने ब्यक्तिगत समूह हिल में अधिक सित्य होते हैं, परन्तु दबाब समूहा के द्वारा सम्बिधत विषयों में विशेषकर तक-नीकी एवं विशिष्ट मामलों में जो आकड़े और तथ्य उपस्थित किये जाते हैं वे प्रशासका एवं विवायका के लिए विधि-निर्माण में प्रयाप्त सहायक होते हैं।

(6) प्रतिनिधित्व के सम्बाध में भी दवाव-समूहा द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निमाई जाती है। प्राय प्रत्येक देश में प्रतिनिधियां का निर्वाचन क्षेत्रीय आधार पर होता है लेकिन मतदाता का हित केवल एक क्षेत्र से ही सम्बाधित नहीं होता हुं ' उसमें जनेक व्यावसायिक, सामाजिक एवं अन्य हित होते हैं। स्मरणीय है कि नीतिक दक्षा के माध्यम से उसव इन विभिन्न हिता वो पूर्ति सम्मव नहीं होती ह। जत समान हित वाले व्यक्तिया द्वारा समूह या सप का निर्माण विद्या जाता है जिसस कि वे शासकीय नीति को अपन हित म प्रमाबित वर सव। अत दवाव समूह व्याव सायिक प्रतिनिधित्व वे लामा वो पूण करते हैं। समाज वे विशिष्ट हिता का प्रति निधित्व करने वे नारण राजनीतिक व्यवस्था म दवाव-समूहा का प्रमावपूण स्थान होना स्वामाबिव होता है। इनके द्वारा शासकीय नीति एव साथजनिव आकाशा के मध्य समय्य स्थापित किया जाता है। दवाव-समूहा तरा विद्यायकर समाज के औषाणिक एव आधिव हिता वा प्रतिनिधित्व विद्यायता है। विधायका को अपने पक्ष म प्रमावित करके दबाव-समूह प्रत्यक्षत जनकत्याण की विद्व में योग देत हैं।

(7) निर्वाचन-काल म प्रतिनिधियों के चयन मे दबाब समूही द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निमाई जाती है। विमिन हित समूहा की विमिन्न दलों में प्रमावपूर्ण स्थिति हुआ करती है क्योंकि राजनीतिक दला को वे समस समय पर आधिक सहायता प्रदान करते हैं। सामान्य निर्वाचन के समय दलीय पत्यादी के रूप म विमिन दबाब समूह अपने उन्मीदेवारों के किए मरसक प्रयत्न करते हैं।

दबाव समूहो की कायपद्धति

अपने उद्देशों की पूर्ति एवं अपनी प्रमावशीलता की बिद्धि एवं स्वायित्व के लिए दबाव समुद्दों द्वारा निम्न उपायों का अनुवसन किया जाता है

- (1) इनके समयन सुदद्ध होते हैं। उनके द्वारा वतनिक प्रचारका (Lobby 1sts) की नियुक्ति की जाती है। उनके मुद्यिज्ञत एव विधिवत कार्यालय होते हैं। य प्रचारक सदद जागरूक रहते हुए विधायका से निकट सम्प्रक एव सम्बच्ध स्थापित करते हैं जिससे कि विधायकों को समृद्ध के हिता के मम्बच्ध म जवगत करने तथा उनकी सहायता प्राप्त करने नथा उनकी सहायता प्राप्त करने नथा
- (2) अपने हितो के सन्य थ म दवाव समृह प्रचार करते है जिससे कि जनमत को प्रनावित किया जा सक। प्रचार के बाबूनिक्तम साथनो जसे कि समाचार पना में चित्रापनो एव लेखों का प्रकाशन, रेडिया एवं टलीविजन ढारर प्रचार पुरतकों तथा सूचना-पित्रकाओं का प्रकाशन आदि का प्रयोग किया जाता है। दवाव समृहों होता विधायक के निर्वाचन कोन के निर्वाताओं से उसे अपने हित ये प्रमानित करने के लिए पन भिजवाने की अवस्था की निर्वाच की नी ने व्यवस्था की निर्वाच लेखा है। शास विवाच स्वाच की नी ने व्यवस्था करते हैं। शास विवाच समझ प्रसान विधायक की नी विवाच स्वाच की नी ने व्यवस्था करते हैं। शास विवाच समझ प्रसान विधायक की विवाच समझ प्रसान विधायक की विवाच समझ प्रसान विधायक की निर्वाच समझ प्रमुल करते हैं।
 - (3) विधानमण्डल करने का ५५ नगरना द्वारा

सिन्य रहते है। प्रमुख आर्थिक समूह अपने स्थायी एजेट रखते है और आवश्यकता पडने पर प्रमुख वकीलों को इस काय ने लिए नियुक्त करते हैं।

(4) विधायको को वे सम्बि बत मामलो म आवश्यक सुचना एव आकडे प्रदान

करते हैं।

(5) दवाय समूह अपने हितो से सहानुभूति एव सहयोग रसने वाले व्यक्तिया को, मले ही वे किसी भी दल के क्या न हो, निवाचनो म विधायक पद वे लिए अपना प्रस्थाशी मनोनीत करने का प्रयत्न करते हैं और विजयी बनाने के लिए हर प्रकार का प्रयत्न करते हैं। निर्वाचना मे दबाव समूहो द्वारा उम्मीददारा का समयन एव विरोध इस बात को ब्यान मे रखकर किया जाता है कि उनके हिता के प्रति उसका क्या इिष्टिकोण है? हितो के प्रति उसका क्या इिष्टिकोण है? हितो के प्रति उसका क्या लिए वे हर प्रकार का प्रयत्न करते है। निर्वाचन मे विजयी होने पर इन विधायको के लिए सहायता करने वाले हित समूहा के हित एव दबाव की उपेक्षा करना सरल नही होता है।

(6) दबाव समुहो द्वारा अपनी उचित एव यायसगत मागा को मनवाने के लिए वध एव खले उपायो का सहारा लिया जाता है। लेकिन कभी-कभी इनके अभि कर्ता अपने स्वाधों की उपलब्धि के लिए अनुचित एवं भ्रष्ट साधना, रिश्वत एवं अप कत्सित उपाया, जसे स्त्रिया का भी उपयोग करते है। विधायका से सम्पक स्थापित करने के लिए वे उन्हें मोज एवं पार्टियों में आमि तित करते हैं । यह ठीक है कि विधायको को केवल मोज देकर ही अपने पक्ष में नहीं किया जा सकता है पर तु इस प्रकार उनस घनिष्ठता बढाने के अवसर तो प्राप्त हो ही जाते है। संयुक्त राज्य अमे-रिका म दबाव समूहो के द्वारा समितिया के सदस्यों को प्रमावित करने का भी प्रयत्न किया जाता है। ब्रिटेन मे दबाब समूहा क लिए ससद सदस्या को व्यक्तिगत रूप से प्रमाबित करना कठिन होता है क्योंकि वहाँ दलीय संगठन अपेक्षाकृत कठोर एवं शक्ति शाली है। अत ब्रिटन म हित समूहो के द्वारा दलो को प्रमावित करन का प्रयत्न किया जाता है या दबाव समूह दल के साथ सगठित हो जात हैं। उदाहरणाथ ध्रमिक समी ने श्रम दल के साथ गठव धन कर लिया है। इसके विपरीत, कृपक सब जनूदार दल स सम्ब धत है। ब्रिटिश दबाव-समूहा द्वारा मित्रमण्डल एव सम्ब धित विमाग के ॥ त्री एव कमचारिया क विचाराधीन विघेषका को भी समृह के हिता के अनरूप प्रभावित करने एव तदनुरूप संशोधित एव अस्वीकृत करने का हुए सम्भव प्रयत्न किया जाता है ।

विभिन्न देशों में दबाव समूहों की स्थिति

सयुक्त राज्य अमेरिका मे दबाव-समूह

संयुक्त राज्य अमेरिका म दवाव समूहा को विशेष स्थान प्राप्त है आर दश की राजनीतिक व्यवस्था म उनकी स्थिति महत्वपूण है। श्री इ एस ग्रिफिस्स क जोुमार, रामुफ राज्य अमरिशा म चार प्रमुख "बाव ममृह है। य राजनीतिक दृष्टि से वापी प्रमायणात्मी हैं। य दवाव-समूह हूँ—स्यापार, पृष्ठि, श्रमिना एव पणन प्राप्त सीना (Veterans) ॥ सम्ब धित समूह । युजना। (aged) स सम्ब धित वोचवें दवाव समूह ना उदय हो रहा है। दिवीय स्वर पर सासनीय ममारिया, नोघा वार्ति, जपमोताओ अत्तर्राष्ट्रीयतावादिया आदि र दवाव समूह है। इसके अतिरिक्त वनीया (अधियक्ताओ) एव डायटरा न मी हित समूह है पर तु व बहुत प्रमायात्मी नहीं हैं। धार्मिन समुदाया स सम्ब धित विक्र समूह हैं वो वेचत न मो कमी ही साव जित्न समसाम म कि लेत हैं। फेडरल नाउ सल ऑक गाउँच ऑक पाइस्ट इन अमरिया ए। दो नसनल न धार्मिन वैवर्षेण ए सामिन सप वे उदाहरण हैं। स्थिया स सम्ब धित अनेन हित समूह हैं वध्या—स्यो मतदाताआ की लीत, अमरिली विग्व विचालया वा महिला समान, व्यवसाया तथा सेवारत महिला समझ, बावि । यह सभी सामत पानिका समान, व्यवसाया तथा सेवारत महिला समझ, बावि । यह सभी सामत पानिका समान, व्यवसाया तथा सेवारत महिला समझ, वावि । यह सभी सामत पानिका समान मानिका समानिका सानिका समानिका समानि

क्षापार एव ध्ययसाया से सम्बिधत मुन्य देशव-समूहा म प्रमुश हैं— वाणिज्यमण्डल (The Chamber of Commerce), निर्माताओं का राष्ट्रीय सप (The
National Association of Manufacturers), अमेरिनन श्रमिक सप, रेस पातायात
प्रभात सप, राान कमचारी सप, औधोगिक सपठना की कविस (The Congress of
Industrial Organisations), अमेरिनन फाम अपूरो, राष्ट्रीय कुपक सथ आदि ।
व्यावसायिक समूहा म प्रमुख हैं—अमेरिनन चिक्तिसा सप (American Medical
Association) राष्ट्रीय विकास सप (National Education Association), इजीनियरों का सप तथा अमेरिकन बार एसीसियसा । दन व्यावसायिक समूहा म दो
प्रकार के समूह होते हैं। प्रमुख तो वे समूह हैं जो सम्पूण व्यवसाय का प्रतितिधित्व
करत हैं एव उसके हित नी इष्टि से काय करते हैं। इस प्रकार के समूहों का एफ
प्रसिद्ध उदाहरण उत्पादनों का राष्ट्रीय सथ है। द्वितीय वे व्यावसायिक सथ या समूह
हैं जा हुख विसिव्य उद्योगों के हिता के सिए ही काथ करते हैं, यथा—रेस पातायत
सभी एवं अमेरिकन पेट्रोलियम सस्थान। इस प्रकार के समूह अपने व्यावसायिक हिती
की रक्षा एवं सवस्थान के विष्य सत्व रूप से सिन्य होते हैं।

धार्मिक संघो के द्वारा भी संयुक्त राज्य अमेरिका म अपने विचारो के प्रवार एव प्रसार तथा हिलो का रक्षाय न्वाव समूहो का निर्माण हुआ है, उदाहरणाय, प्राटेस्टेट चर्चों को राष्ट्रीय समिति ने रमभेद के मामला म रूचि ली थी। परान प्राप्त सैनिका एव देशमक्तो के संघी (Patriotic Front) की सदस्य संस्था बहुत बड़ी है।

⁹ नीत्रो जाति क हितसमुह का एक उदाहरण काल व्यक्तिया एव रित्रया का राष्ट्रीय विकास सम (The National Association for the Advancement of Coloured People and Women) है ।

इस प्रकार के प्रमुख समूह है अमेरिकन लेजियन (American Legion) तथा विदेशी युद्ध ने वद सैनिक समूह (The Veterans of Foreign Wars)। दोनो प्रकार के उपरोक्त सप रेश की राजनीति म सिक्रम भाग नेते हैं। अमेरिका म कृषि से सम्बर्धाय में शित में तो प्रकार के क्या था समुदाय हैं। एक जो समूच उद्योग के हिती का सर्काण एव प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार के समूच उद्योग के हिती का सर्काण एव प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार के समूच क उद्योग के हिती का सर्काण एव प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार के समूच क उत्याहरण हैं अमेरिकन काम स्पूर्त फेडरेशन (The American Farm Bureau Federation) एव राष्ट्रीय सम्पूण कृषि उद्योग से सम्बर्ध पति हिता की रक्षा की जानी चाहिए और कृषि सम्बर्ध सामान्य मोति, जसे कि कृषि उत्याद के पूनतम मूच्यो का निर्धारण एव अमेरिकी कृषकों की विदेशी उत्यादक जीनत प्रतियोगिता से सुरक्षा के निर्धाण का प्रवादक स्वादिश । इस प्रकार का कि नार्ध भी कुछ समूह होते हैं प्रधा— समिष्क तोयाबीन सथ । इस प्रकार का एक बन्य उदाहरण दुध उत्यादका का राष्ट्रीय सहयोगी सथ (The National Co operative Milk Producers Federation) है।

सभी प्रमुख दवाव समूहों क राष्ट्रीय एव राज्य स्तर पर सगठन होते हैं। इन दवाव समूहों की स्थानीय इकाइयाँ ज्ञाम या नगर-प्रवाध स सुधार के लिए प्रयत्तवील रहती हैं। समाज विकास सथ (The Community Improvement Associations) प्राम या नगर म प्रकाश एव पुलिस प्रवाध पर नगर रखते हैं। इन सथा के हारा जनता का अधिकतम सहसोग प्रास्त करने के लिए प्रवास भी किया जाता है।

हुजारा प्रवान समूहा ने अमरिकी राज्यानी वासियटन म अपने कामालया की स्थापना कर रखी है । इनके द्वारा अपने हिता के सबद्धन के लिए जिन प्रवारको या अमिकतीओं को नियुक्त फिया जाता है, वे विधि निर्माण और प्रवासिक संगठन एव कामपदित की बारीकिया से मली स्कार परिचित होने हैं। अधिकास ममूहा ने अमिकता पत्रकार महिता से कही हो, मृतपूज कामस्तान एव अवकास प्रास्त उच्च पदाधिकारियों के वग म से चुन जाते हैं और उन्ह पर्याप्त वेतन दिया जाता है।

अमेरिका मे बनाव समूही के विकास के लिए उपमुक्त बातावरण है और निम्नाकित तत्वा ने अमेरिकी राजनीतिक जीवन म इनके विकास म योग दिया है— (1) पिषिल दसीय समछन, (2) विचार एव अध्विष्टा की स्मत बता, (3) स्वतंत्र्य विधि निर्माण प्रतिन्या पानी सभी के लिए विधि निर्माण प्रतिन्या को प्रमावित करने के अवतर, (4) शासन का ध्यापक कायबेट। सयुक्त राज्य अमेरिका म ससद प्रधान देश की माति विधि निर्माण एव धान्यजीनन नीतियो पर ससद के बहुमत दल का एकाधिकार नहीं है। अमेरिका म तो समी विध्यक कम्मित के सदस्यो द्वारा प्रसावित किय जाते है। अमेरिका म तो समी विध्यक कम्मित के सदस्यो द्वारा प्रसावित किय जाते हैं। जो ऐसी स्थिति में विभिन्न द्वाव-स्पृहा द्वारा विधि निर्माण को प्रमावित करना सरल हाता है। समुक्त राज्य अमेरिका मं दबाव समुद्दां का विशेष महत्व है। उन्हें विधान मण्डल के ऐसे त्वीय सदन की सजा दी वाजी है जो सविधान को सीमा के वाहर काय करते हैं। वे अत्यधिक प्रमावज्ञाली होते हैं। लास्कों ने दबाव समुद्दों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि न्वाव समुद्दा में स्पष्ट असर्गति होते हुए भी इनकी सत्ता को कम नहीं समभना चाहिए। सदन वे सदस्य के लिए वे बहुत कुछ कर मकते हैं। उसके मापणों को तैयार करके वे उसकी सहायता कर सकते हैं, उसका ऐसा प्रचार कर सकते हैं असकों उसे कोई आशा न हो। सभी प्रचारकों का प्रमुख समावाद-पत्रों की ऐजेंसियो, पनकारों आदि स परिचय होना है। यदि प्रचारकंगण चाहें सो विधायक को राष्ट्रीय क्याति प्रवान करा सकते हैं यदि कांग्रेस के किसी सदस्य को योग्य प्रचारका का से से बाएँ उपयुक्त समय पर उपलब्ध हो जाती है तो वे उसके राज नितिक जीवन म निर्णायक प्रमाणित होती है। अमेरिकी दबाव समुद्दों के डाए स्थायी कर से सिंसी मी दल का समयन नहीं किया जाता है। उनके लिए उनके हित सविपिर होते हैं एव अपनी स्थित को सुद्ध दखने के लिए वे दलों को परस्पर लड़ाने का भी प्रयास करते रहते हैं। दोनों दलों म अपनी स्थिति को सुद्ध रखने के लिए वे दलों को परस्पर लड़ाने का भी प्रयास करते रहते हैं। दोनों दलों म अपनी स्थिति को सुद्ध रखने के लिए वे दलों को परस्पर लड़ाने का भी प्रयास करते रहते हैं। दोनों दलों म अपनी स्थिति को सुद्ध रखने के लिए वे दलों को परस्पर लड़ाने का भी प्रयास करते रहते हैं। दोनों दलों म अपनी स्थिति को सुद्ध रखने के लिए वे दलों को प्रवास करते हैं। दोनों दलों म अपनी स्थिति को सुद्ध रखने के लिए समय समय पर दोनों दला को आधिक सहायता प्रवास करते हैं।

प्रेट विटेन में दक्षाव समूह

ग्रेट ब्रिटेन म दबाव समूह नवीन नहीं हैं लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की माति दवाव समूहा का वहाँ महत्व नहीं है। 19वीं सदी में चार्टिस्ट आ दोलन एवं अनाज-विरोधी सम (Anti Corn Law League) समक्त एव कियाशील दवाव समूह थे। आधुमिक ब्रिटेन म इनकी सच्या म बिंद हुई है। ह्वीयरे के अनुसार ब्रिटेन मे 'सायद ही ऐसा कोइ व्यवसाय है जिस पर देश की किसी समिति के विचार करने पर उस समिति के समक्ष उस व्यवसाय के हितो का प्रतिनिधित्व करन वाला कोई समुदाय न हो। ' ब्रिटिश दयाव समूहा को वर्गीकृत करना कठिन है। विभिन्न आर्थिक हितो क सरक्षण करन वाले प्रमुख दबाव समूहा य ब्रिटिश औद्योगिक सघ (The Federation of British Industries), यातायात एव सामा य श्रीमक नथ (Transport and General Worker's Union), खनिज श्रमिको का राष्ट्रीय सघ (The National Union of Mine Workers), बहाज निमाण कमचारी सथ वस्त्र कारखाना श्रमिक सघ आदि प्रमुख हैं । इन सघा की विभिन्न एवं घटक इकाइयाँ भी हैं । इनसे कम महत्व पुण दवाव समूहा मे 'बूश निर्माताबा का राष्ट्रीय समाज या प्लम्बरा की राष्ट्रीय सोसाइटी आत हैं। ब्रिटेन म किसी व्यवसाय के मालिका द्वारा मिलकर भी सप या सगठा का निर्माण कर जाता है। र एव उद्योगासे सम्बर्धित ही वेवल हित-समूह न[्] हितो स सम्बर्धित भी समह

पाय जात हैं। कमी-तनी स्थानीय सस्थारों अय सायजनिक सस्थाज या शासकीय विमायों से मिलकर कियी विशेष हित के सबद्धन न लिए सथ या सगठन का निर्माण कर तेती हैं, यथा—राष्ट्रीय आवाम एवं नगर निर्याजन समिति। जिटन म विचार-धाराओं से सम्बिप्त अनव समूह है। इनका उद्देश्य विभी विश्वास या विचारधारा का प्रवाद करना होता है, जम हि राष्ट्रीय पुत्र-यान निषेष समिति, जानवरों ये प्रति करोता निषेप समिति, जानवरों ये प्रति करोता निषेप समा । शिक्षाण वा भी राष्ट्रीय सप है। इनका उद्देश्य विशोध के काम ने पण्ड, वेतन एवं सवा ही परिस्थितिया म पूथार का प्रयस्त वरना है।

प्रट विटन म दबाव समूहा ना मा जा ही गयी है और व सासन के अंग के रूप म स्वीकार किय गय हैं। सासकीय विमाना ने समध दवाव समूहा को उपस्थित हान एव विचार प्रस्तुत करने वे पूर्ण अवसर प्राप्त हात हैं तथा इसरा वे पूर्ण लाभ में उठाते हैं। अभिका स सम्बिध्त अम स्वा एय मानिया च सथा ने मूची अम मानावय द्वारा प्रकाशित दायरम्टरी म दो जाती है। सम्बिध्त सस्याआ एव सथा से सासन द्वारा प्रकाशित प्रदानों ने सम्बाध म प्रामदा किया जाता है और सासन एव हित समूहा म आप दिन विचार विमय एव प्रामदा किया जाता है और सासन एव हित समूहा म आप दिन विचार विमय एव प्रामदा किया जाता है और सासन एव हित समूहा म आप दिन विचार विमय एव प्रामदा होते रहते हैं। ब्रिटेन म ससदीय ध्यवस्था के कारण समूहा मा विधायका एव समितिया क सदस्या क मध्य प्रचार से क्षत्र माना कि काइ आदा नहीं होती है। प्रियमण्डल नीरित करता है अत मित्रमण्डल को हो ब्रिटिश दाज समूह प्रमावित करता है और मित्रमण्डल को ही ब्रिटिश दाज समूह प्रमावित करता है और मित्रमण्डल को अभन हित स प्रमावित करने मा प्रयस्त करता हैं। इसके अविरिक्त अनेक द्वाव-समूहों का हता से प्रमावित करने मा प्रयस्त करता हैं। इसके अविरिक्त अनेक द्वाव-समूहों का सता से पित्रद सन्य प्रहात है, उदाहरणाप, अमिन सगटन थम दक्त स एव इपक मय प्रमान अनुदार दल स सम्बध्त है।

ब्रिटेन म अनंक द्याव समूहा के अुष्य कायासय प्रिटिश ससद के समीप ही हैं। वे ससद या उनकी समितियों म उपस्थित नहीं होते हैं, पर तु उह ताही आयोगों के समक्ष विवार व्यक्त करन वा अधिकार प्राप्त हैं। वे निर्वाचन काल म प्रचार करके विधायका का प्रभावित नहीं करते हैं। दिने में राजनीतिक हलों का प्रधाय है एवं उनका अपने सदस्या पर पूण नियायण होता है। कॉम स की समितियां अधि-रिकी समितियों की अधेक्षा वडी होती है। किं जु उनकी मीति शक्तिशाली नहीं होती हैं। विटिश समितियों के कार्यों का निर्देशन भी खलां क द्वारा ही किया जाता है और मारी उनका निर्देशन भी खलां क द्वारा ही किया जाता है और मारी उनका नेतृत्व एव माग दशन करते हैं। मित्रमण्डलीय उत्तरदायित के सिद्धा तथा मित्रमण्डल के समठन के कारण हित समूहों के लिए प्रचार की कोई गुंबाइश नहीं है। अत विटिश दवाव समूह समाचार पत्रों के माध्यम से मतदाताओं को प्रमावत करने वा प्रयत्त करते हैं। उनके समक्ष अपने हितों की पूर्ति सम्बाधी तीन

विकल्प हैं (1) जनमत को प्रमावित करना, (11) ससद मे अपना प्रतिनिधि भेजकर अपने हित का सरक्षण करना, एव (111) धासन को प्रमावित करना। 11 अमेरिकन कांग्रेस की मौति कोंगस समा के दबाव समूहो द्वारा अपने हित मे विधायका को प्रमावित करने हेतु प्रचार काय नहीं किया जाता है। अनेक अवसरो पर ससद एव उसकी दीर्घाओं में हित समूहों के प्रचार (Lobbyung) को ससदीय विश्वेपाधिकार का हनन घोषित किया गया है और यदि सदस्यों को प्रमावित करने के लिए रिक्वत, हिंसारमक धमको, अपसाब्त, आर्थिक हानि पहुँचाने के प्रयत्न किये जाते है तो ऐस कार्यों को बण्ड नीय अपराब धोपित विया गया है। निश्चय ही कुछ ससद स्वया को बाह्य सस्याओं द्वारा आर्थिक सहायता दो जाती है लेकन ब्रिटिश ससद के नियमानुसार ऐसी स्थिति में सम्बिधन सदस्य सह व्यस्त के समझ यह उत्यस्त्रीकार करेगा कि बहु अमुक निजी हित से सम्बधित है तथा कुछ अवस्थाओं यह सदन में मतदान से पूषक रहेगा।

प्रश्न यह है कि ब्रिटिश ससदीय सदस्य एवं किसी बाह्य हित में क्या सम्बन्ध होने चाहिए ? इस सम्बन्ध म एक विवाद 1947 ई मे ब्रिटिश ससद क समक्ष आया था। एक ब्रिटिश संसदीय सदस्य लोकसेवा लिपिक संघ से सम्बन्धित या एवं वह उसका स्थायी महासात्री था । बाद म कुछ मतभेद उत्पन्त हो जाने पर सम ने उसे सवेतन एव बोनस पर अवकाश शहण करने के लिए तैयार कर लिया। सध के दबाव से अपने को बचाने के लिए उसन सदन से प्राथना की कि सब द्वारा ससदीय सदस्य को अपन विचारों के विरुद्ध बोलने के लिए वाध्य करके सब द्वारा ससदीय विशेषा धिकार का अतिक्रमण किया गया है। उसकी इस प्राथना पर कॉम स समा की विशेषा-धिकार समिति न विचार निया । समिति का मत था कि संघ द्वारा ससदीय विद्योषा धिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है। साथ ही साथ समिति का यह भी मत था कि समदीय सदस्यों को किसी बाह्य संघ से सम्बन्ध रखना एवं आर्थिक लाम प्राप्त करने से उसकी स्वत नता का अनुचित रूप में हनने होता है। इस मामले के फल स्वरूप 1947 इ. म काम स समा ने एक शासकीय प्रस्ताव स्वीकार किया जिसके अनुसार ससदीय विशेषाधिकार एवं भाषण की स्वतः त्रता की हष्टि से यह सवया असगत माना गया कि ससद का कोई सदस्य किसी ऐसी वाह्य सस्या से सम्बाध रखे और जिसके फलस्वरूप उसकी स्वाधीनता एवं काय की स्वत नता सीमित होती हो । दिसम्बर 1947 ई में कॉम स सभा ने एक व य प्रस्ताव पारित किया है। इसके अनुसार यदि कोई सदस्य रिश्वत लेकर गुप्त सूचना प्रगट करने एव प्रकाशित करने का दोपी ठहराया जाता है तो रिश्वत देने वाला भी सदन का कोपशाजन होता है एव परिस्थितियों के अनुकल सदन को कायवाही करने का अधिकार प्रदान किया

¹¹ Finer op at, p 464

गया है। अत प्रचारको या दबाव समूहो के अभिकर्ताओ (Agents) की दण्डित करने की द्विटेन म उचित व्यवस्मा है।¹³

क्रास मे दबाव समूह

फास म सामाजिक, आर्थिक एव धार्मिक विचारधारावा से सम्बर्धित अतेक दबाव-समृहो का अस्तित्व है। फा स म केवल वाधिक एव श्रमिक हिता का प्रतिनिधित्व करने वाले सघा को ही दबाव समूहो म शामिल नही किया जाता है अपितु प्राविधिक, प्रधासनिक एव समाचार-पत्र तथा चच एव विश्वविद्यालया की विचारधाराजा स सम्बन्धित सब भी दवान समहो की थेणी म आते हैं। चच से सम्बन्धित दवाद-समहा का उदाहरण कैथोलिक चच सगठन है। विचारधारामा से सम्बन्धित दबाव-समृह विभिन्न विचारा का समयन करके राजनीतिक जीवन की प्रमावित करत है। समाचार-पत्र भी इसी श्रेणी मे आते हैं। फ्रांस म दवाव-समृहों का विद्यास संयुक्त राज्य अम-रिका एव ग्रेट ब्रिटेन से सबया भिन्न रूप म हवा है। बहुदनीय पद्धति इसका प्रधान कारण है। फास में अनक छोटे-छोट दला का उदय हजा है जिसके जाधार छोडीच एवं अप हित है। अनेक छोटे दलों का अस्तित्व देवन मसद तक ही सौमित है। इन्हें छोटे राजनीतिक समृहों (Splinter groups) की बचा दी बादी है। प्राम म राजनीतिक दली एवं इन छोट छोट राजनीतिक सनुरों के नन्य विमाजन-रखा सीचना कठिन है। विभिन्न स्वायों एवं हितो हारा इत उहन्हाद राजनीतिक दना व साय गठव धन कर लिये जाते हैं, उदाहरमान, यनिक चर्रों का बानरशीय दशा स यनिष्ठ सम्बद्ध ह । एन आर पी (Popular Regressian Movement) मध्यम दा एव कैयोनिक जनता के हिता हा सा के निर्न्द नहेंब बारूक रहता है अस उस सहय ही उनके समयन की पूण बाजा हुना है। उन्तेय क्षेत्रा के हिना का अतिनिधि र

²¹⁴ | आधुनिक शासनत[्]त्र

ने य देशों म व्यापार मण्डला (Chamber of Commerce) की स्थिति अड सास नीय अधिकारी जसी है। व्यापार मण्डलों के अधिनारिया की स्थिति अब सास कीय कमचारियों के समान थी और शासन द्वारा उन्हें महत्वपूण काय सीपे जाते थ । अ महाद्वोषीय देवी म एक अय प्रवित्त का भी विकास हुआ है । शासन द्वारा इन समूहा या सघो को आधिक सहायता देन की व्यवस्था थी। य समूह अधिकारियो हारा स्वीहत सासन की नीतियों का प्रचार तथा विषयीत नीतियों का किरोध क थे। मा सीसी सरकारों ने देशमक्ति एवं समान कार्यों का प्रचार करने वाले समुदाः को बढावा दिया है। जदाहरण के लिए, पेरिस म अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थों सप को सास कीय सहायता दी गयी थी। अत स्पष्ट है कि कास म दवाव समूह काफी सन्त्रिय एव प्रमानसाली हैं। पाँचवे गणराज्य के अवगत आधिक एव सामाजिक परिपद (The Economic and Social Council) की स्थापना दवाव समूही की ही विजय हैं। सवप्रवस जमन आधिक परिपद के आधार पर प्राप्त म एक आधिक परिपद की ही स्पापना हुई थी। चतुम गणराज्य म इसे कायम रखा गया था (अनुस्वस 25)। इसके अतिरिक्त का से के चतुष गणत नीय संविधान के अतगत असे स्वती म स्थानीय एव व्यावसायिक हितो या व्यक्ति के रक्षाय हित-संप्रहो के निर्माण का निर्देध किया गया था (अनुक्छेद 13) और अपने यह का दुरुपयीय करते हुए किसी वित्तीय या औद्योगिक संस्थान से लाम प्राप्त करने का दोषी पाये जाने की अवस्था म विधायको के लिए दण्ड एव निष्कासन की व्यवस्था की संयी थी (अनुच्छेद 119)। मा स म द्राव-समूहो के प्रमाव के कारण उहे राज्या तसते राज्य, आविक परिवद (Economic Congregation) एव नवीन साम ती लाडी (Neo Feudal Loi की सना दी जाती है। जापान में बबाब समूह

्रितीय विश्वयुद्ध क पून जापान की शासन व्यवस्था म सैनिक अधिकारि का विदाय प्रमाव था। सर्वोच्च युद्ध परिषद (Supreme War Council) का सन्द्रा मा (वर्षात्र नार्षात्र मा । दोना सुरक्षा विमाना के बच्चकी मुख्य सनिक एव नो सैनिक अधिकारियो (Chief of Staffs) तथा सम्राट द्वारा मनोनोत सदस्य पुत्र पा वागण आवशासका १०००० व्यास्त्र अस्त वास्त्र वास्त्र स्वाचन युद्ध परिवद के सदस्य होते थे। घीटे घीटे यह परिवद करविषक वानितसासी होती वली गयी और नामरिक सासन को सनिक एव वसैनिक सभी क्षेत्रों में प्रमा हता वधा पत्र कार्य । वित करने तभी । सनिक एव नौ-सनिक विभाग कं मत्री सैनिक अधिकारी ही हुआ भव भव विश्व है सना तथा नो सेना को मृत्रिमण्डल को नीतियो एवं मन्त्रिमण्डल करत था १४५८ ह छ। एक भाकित करने के पर्योच्च अवसर थे । मुख्य सनिक

अधिकारिया को प्रधानमात्री के निषयों के विरुद्ध सम्राट से सीये अपील करने का अधिकार था । स्पष्ट है, युद्धोत्तर-पून जापान में सेना सर्वाधिक प्रमानशाली दवाव-समूह था । सिनक अधिकारियों का औद्धोगिक एवं व्यापारिक हिंतों से घनिष्ठ सम्व प । जापान के चार प्रमुख औद्धोगिक परिवार—मितसू, मिस्नुनिसी, सूमि-तोमो एवं यशोदा—िल हुं सामूहिक रूप म जियवस्तू (Ziabatsu) कहते थे तथा जो देश के प्रधान 150 औद्योगिक प्रतिकानों के स्वामी थे सैनिक अधिकारियों एवं सामत से घनिष्ठत सम्बच्धित थे। प्रधान राजनीतिक दक्षा का मी इस सम्बचिशायी वम से सम्बच्ध होने के कारण उन्हें प्रभूत आधिक सहायवा प्राप्त होती थी। अत

जियबत्स सेना के अतिरिक्त दिलीय प्रधान दवाव समह या।

युद्धोत्तर काल, दितीय विश्वयुद्ध के पश्चात जापान से इन सैनिक एव पूजी वादी के दा का लाहमा कर दिया गया तथा बड़े श्रीवोगिक एवं बैकिंग सस्थाना को समाप्त घोपित किया गया। चार प्रमुख औद्योगिक परिवारा की सम्पत्ति छोटे छोटे मागो म विमाजित कर दो गयी। विकिन यह स्थिति अधिक समय तक न चल सकी। सयुक्त राज्य अधेरिका को 1947 ई में अपनी इस नीति को परिवृत्तित करना पढ़ा एवं औद्योगिक परिवारी ज्यिवत्त् की पुन स्थापना हुई। 1953 ई के अन्त म औद्योगिक फर्नो ने अपने को पहले की मौति पुनपठित कर तिया है एवं 1954 ई में पुराने मिस्सूविद्यो औद्योगिक प्रतिस्ठान की पुन स्थापना हुई है। वतमान जापान के अनुदार एवं उदारवादी लोकताजिक दल अग्रुद्ध के पूत्र के सिद्धकाई (Sciyukai) एवं मिनसीटो (जन राजनीतिक दल Minseito) का प्रतिस्था है। इन दलों के औद्योगिक प्रतिस्ठानों वे पहले की माति हो सम्ब च स्थापित हो गये हैं। 1947 ई से सेना का भी पुनपठन किया गया। बता आधृनिक जापान म युद्ध-पूर्व जापान के माति के दबाव समहा की स्थापना हुई है।

जापान मे अनेक प्रमुख दवाव समूह है । इनम सबसे अधिक शक्तिशाली दवाव समूह श्रीयावृत्त (Oyabun) है । सारे देश के गाँवा एव तथरों म इसके सगठन का जात फीता हुआ है । नगरों मे इसके द्वारा श्रीयको, जूआयार, निर्माण योजनाजा, राजनीतिक दलीय सगठनों एव असामाजिक तत्वों को नियत्रित किया जाता है । प्रामीण क्षेत्रा में यह सगठन कुपकों पर नियत्रिण एवता है। एक अन्य दवाव समूह 'हरित समीर समाज' (Green Breeze Society) है। यह अनुदारवादी विचारधारा का सगठन है। इसके अतिरिक्त आर्थिक सगठनों का सथ, कमचारी सप, ज्यापार एव वाणाज्यमण्डल, प्रवाध सप आदि अन्य आर्थिक सथ हैं जो नियस्तित रूप से सम्बधित हितों के रक्षाय तोष तथ्या का विश्वतेषण एव अस्तावन करत रहते हैं। विभिन्न श्रीमक सप मी हैं। इनके अपने राष्ट्रीय सगठन भी हैं। इन श्रीमक सधा म लाखा की सस्या में सदस्य हैं। 'जागानी श्रीमक सर्थ एव 'जापान व्यापार करिस स्वप प्रमुख प्रमिक

सगठन हैं। इपि सहयोगी सघ क्रिय हिता का प्रतिनिधित्व करन वाला प्रमुख हित समूह है। इसके 45 हजार स्थानीय इपक सहयांगी सघ हैं। इसके अतिरिक्त पे उन प्राप्त अधिकारिया एक सिनको पत्तिया दिश्यो आदि के पृथक-पृथक सामाजिक द्वाय न्यमूह है। इन दवाव समूहों के राष्ट्रीय एव स्थानीय स्तर पर सगठन एवं समाएँ है। अपने हितो के रक्षाथ इनके डारा प्रचार, साहित्य वितरण एव प्रतिनिधि मण्डल आदि नेजकर सामन तथा विषायकों को प्रशाबित किया जाता है। जानान में दवाय-समूहों को अहस्य सासन (Unseen Government) नी सन्ना दी जाती है। भारत में दवाय-समूहों को अहस्य सासन (Unseen Government) नी सन्ना दी जाती है। भारत में दवाय-समूहों को अहस्य सासन

नारत भ दवाव-समूहों का विकास पाश्चात्य देशों की मांति नहीं हुआ है और उनकी सख्या मी अधिक नहीं है। भारत में चार निम्न प्रकार के दवाव-समूह पाये जाते हैं

- (1) बिशेष हित-समूह—इस श्रेणी मे प्रधानत आर्थिक एव व्यावसायिक, श्रमिक वग, सहकारी सस्याओ, कृपको समाज-कल्याण एजेसियो, शिक्षक, विद्यार्थी एव सास्कृतिक हितो से सम्बन्धित हित-समृह आते हैं।
 - (2) साम्प्रवायिक एव धानिक सस्याएँ ।
 - (3) जाति एव नाया पर आधारित समूह या सस्याएँ।
 - (4) गाधीनादी विचारधारा का प्रतिनिधित्म करने वाले सगठन ।

अभिक सध-विधेप हित समुही क अतगत थमिक सघी का मुख्य स्थान है। इनकी सरया बढ़ी तेजी से बढ़ रही है। अखिल मारतीय देड यूनियन काँग्रेस, इण्डि यन नेशनल देख यूनियन काग्रेस, हिन्द मजदूर समा एव यूनाइटेड देख यूनियन काग्रेम देश के चार प्रमुख श्रमिक सघ हैं। इनकी सदस्य सख्या 40 लाख से भी अधिक है तथा इन सगठना की इकाइया की सख्या 3500 के करीब है। यह सभी श्रमिक सप देश के प्रमुख दलों सं सम्बंधित हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन काग्रस मारतीय साम्यवादी दल से, इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन काग्रेस स हिन्द मजदूर समा समाज वादियो एव युनाइटेड ट्रेड युनियन काँग्रेस साम्यवादिया से सम्बन्धित है। अखिल भारतीय देड यूनियन काँग्रेस इन सब म सबसे प्राचीन संगठन है । अपने प्रारम्भिक समय म यह कांग्रेस के प्रभाव में थी। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में बस्त उद्योग श्रमिक मघ की स्थापना की थी। 1929 ई मे अखिल मारतीय ट्रेड यूनियन काग्रेस पर साम्यवादिया का नियात्रण स्थापित हो गया था। प्रो डेविड मोरिस का मत है कि मारतीय श्रमिक सब (Trade Unions) न तो दबाव समृहो और न राजनीतिक दलो के रूप म ही काय करते हैं। उनका संगठन तो मध्यवर्गीय नेताओ द्वारा राजनीतिक दला के अंग के रूप में किया जाता है। फलस्वरूप कांग्रेस सरकारों को अनेक बार श्रमिको को अनुदासित करने एव अनेक बल्याण के लिए राज्य-शक्ति का प्रयोग करना

पडा है। ¹⁴ मारत मे श्रमिक सघो का नगरों के श्रमिक क्षेत्रों में ही केवल व्यापक प्रमाव है।

वाणिज्य, ब्यावसायिक एव औद्योगिक सघ-उद्योगपतिया एव व्यापारियो के कुछ प्रमुख सघ हैं, यथा--फैडरेशन ऑफ इण्डियन चैम्बर आफ कॉमस एण्ड इण्डस्ट्रीज (FICCI), मारवाडी चैम्बर ऑफ कामर्स, मुसलिम चैम्बर ऑफ कॉमस, उत्तर प्रदेश वाणिज्य व्यापार मण्डल आदि । FICC I का मूख्य कार्यालय नई दिल्ली म है। उनका अपना सोध प्रतिष्ठान भी है। व्यापारिक सघी के कुछ उदाहरण है मिल मालिक सघ, मारतीय मालिकान सघ आदि । मारत मे कुछ प्रमुख व्यावसायिक समुदाय भी हैं, जसे--मारवाडी, पारसी, गुजराती समुदाय आदि । वे स्वय अपने आप में काफी प्रमावशाली हैं। भारतीय उद्योग जगत पर कुछ परिवारों का आधिपत्य है, जैसे—विरला, टाटा, बालचन्द जैन, सिंघानिया, गोइनका एव डालिमया परिवार । यह परिवार स्वय अपने आप में शासन की नीतियों को अपने हित में प्रमावित करने की क्षमता रखते हैं। इनके द्वारा मुक्तहस्त होकर सावजनिक कोषो म सहायता एव दान एव राजनोतिक दलो को आधिक सहायता प्रदान की जाती है। शासन के उच्चा-धिकारियो एव मित्रयो के पुत्रो एव सम्बर्धियो को अपने प्रतिब्हानों मे नौकरी आदि प्रदान करके वे उनसे निकट सम्पक स्थापित करने में सफल होते हैं। इन परिवारो का देश के समाचार पत्रो पर पूण नियात्रण है। बहुत से ससद सदस्य इनके प्रभाव म होते है। फलस्वरूप ससद म इनकी वात व्यानपूर्वक सुनी जावी है। मारत म समाज-वादी व्यवस्था की स्थापना को लक्ष्य अपनाय जाने पर 1956 ई से भारतीय व्यापा रियो ने स्वतात्र उद्योग फोरम (Forum of Free Enterprise) की भी स्थापना की है।

कृपक सप--मारत म कृपक सगठन श्रमिक सपो की अपेक्षा कमजोर है। प्रथम किसान समा की स्थापना 1936 ई में हुई थी परंतु यह सगठन सिन्न्य नहीं रहा। चतुष ससद काल म कृपक फोरम की स्थापना हुई थी। इसके द्वारा किसानी पर आय कर सगाये जान का विरोध किया गया है।

विद्यार्थी सगठन—हर विद्यालय एव विश्वविद्यालय स विद्यार्थियो के सगठन हैं और अखिल भारतीय स्तर पर इन विद्यार्थी सगठना का गठन किया गया है। विभिन्न राजनीतिक दता से ये सगठन सम्बन्धित हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी सप साम्पवादी दल से, विद्यार्थिय ते राष्ट्रीय सभा कांग्रेस स एव विद्यार्थी परिपद जनसप से सम्बन्धित है। विभिन्न राजनीतिक दलो स सम्बन्धित होने के कारण ये विद्यार्थी सगठन एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी सगठन वन गये हैं। सभी विद्यार्थी सगठन प्रादेशिक, क्षेत्रीय एव स्वानीय आधार पर सगठित हैं।

¹⁴ M G Gupta op cst, p 227

सगठत हैं। कृषि सहमोभी सम कृषि हिता का प्रतिनिधित्व करन वाला प्रमुख हित समूह है। इसके 45 हजार स्थानीय कृषक सहयोगी सम हैं। इसके अंतिरिक्त पे रान प्राप्त अधिकारिया एव सैनिको, पित्तयों हित्रयां आदि के पृथक-पृथक सामाजिक दवाव समूह है। इन दबाव समूहों के राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर सगठन एवं समाएँ हैं। अपने हिता के रक्षाय इनके द्वारा प्रचार, साहित्य वितरण एवं प्रतिनिधि मण्डल आदि भेजकर सासन तथा विधायका को प्रमाखिन किया जाता है। जापन में दवाव समूहों को अह्म्य सासन (Unseen Government) की सज्ञा दी जाती है। भारत में बबाब समूहा को अह्म्य सासन (Unseen Government) की सज्ञा दी जाती है।

मारत प दबाब-समूहो का विकास पारचारय देशों की मौति नहीं हुआ है और उनकी सक्या भी अधिक नहीं है। भारत में चार निम्न प्रकार के दबाब-समूह पाये जाते हैं

- (1) किमोप हित-समूह—इस श्रेणी मे प्रधानत आर्थिक एव व्यावसायिक, श्रिमिक वग, सहुकारी सस्याओ, कृषको समाज कल्याण एवेसियो, शिक्षक विद्यार्थी एव सास्कृतिक हितो से सम्बन्धित हित समूह आते हैं।
 - (2) साम्प्रदायिक एव धार्मिक सस्याएँ ।
 - (3) जाति एव भाषा पर आधारित समूह या सस्थाएँ।
 - (4) गाधीवादी विचारमारा का प्रतिनिधित्व करने वाले सगठन ।

श्रमिक सघ-विशेष हित समुही के अत्तरात श्रमिक सद्या का मुख्य स्यान है। इनकी सरपा बड़ी तेजी स वढ रही है। अखिल मारतीय टेड युनियम काग्रेस, इण्डि यन नेशनल देड युनियन कांग्रेस, हिन्द मजदूर समा एव युनाइटेड ट्रेड युनियन कांग्रेस देश के चार प्रमुख थानिक संघ है। इनकी सदस्य संख्या 40 लाख से भी अधिक है तथा इन सगठना की इकाइया की सरया 3500 के करीब है। यह सभी श्रमिक सप दश के प्रमुख दलों से सम्बचित है। अखिल मारतीय देह ग्रुनियन काग्रेस मारतीय साम्यवादी दल से, इण्डियन नेशनल टड यूनियन कांग्रेस से. हि द मजदर समा समाज वादियो एव युनाइटेड ट्रेड युनियन काँग्रेस साम्यवादिया से सम्बन्धित है। अखिल भारतीय देंड युनियन काँग्रेस इन सब म सबसे प्राचीन संगठन है । अपने प्रारम्भिक समय में यह कांग्रेस के प्रमान में थी । महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में बस्य उद्योग श्रीमक सघ की स्थापना की थी। 1929 ई में अखिल मारतीय टुंड यूनियन कांग्रेस पर साम्यवादियों का नियात्रण स्थापित हो गया था। त्री डविड मोरिस का मत है कि भारतीय श्रमिक संघ (Trade Unions) न ता दवान समृहो और न राजनीतिक दली के रूप म ही काय करते हैं। उनका संगठन तो मध्यवर्गीय नेताओ द्वारा राजनीतिक दलों ने अग के रूप म किया जाता है। फलस्वरूप काँग्रेस सरकारा को अनेक बार धिमको को अनुशासित करने एव अनेक क्ल्याण के लिए राज्य-शक्ति का प्रयोग करना

उनको 'अहरय सरकार', 'विधानमण्डल के पीछे विधानमण्डल', 'अज्ञात साम्राज्य' एव 'सह-सरकार' की सजाएँ दी जाती है। इन दवाव समुहो द्वारा अपने उद्देश्य पूर्ति के हर साधन, उचित एव अनुचित भ्रष्ट साधना, रिश्वत, स्त्रिया, धनादि का अपने हित साधन के लिए प्रयोग किया जाता है। समाज म निमिन्त नर्गों एन हिता की बद्धि के फल-स्वरूप दवाव या हित समुहा का विकास स्वामाविक एव वाछनीय है। लॉवीइग को आज अनुचित मानना समय के अनुरूप नही है। दबाव-समृहो के द्वारा प्रयोग किय जाने वाले अनुचित तरीको के प्रति आपत्ति का होना स्वामाविक ह । पर तु प्रश्त है कि वे ऐसा क्यो करते है ? उनके हारा अनुचित, भ्रष्ट एव उत्कोच के साधना का प्रयोग क्यो किया जाता है ? क्या इसका यह अथ नहीं है कि हित समहों को निया जित एव सुधारने की आवश्यकता है। यह कहा जाता है कि दवाव समुहा द्वारा व्यक्तिगत हितों को प्रश्रय देकर राष्ट्र की आत्मा को खण्डित किया जाता है। क्या यह आराप सस्य है ? लोकतान का महत्वपूष सिद्धात विचार स्वात व्य एव समुदाय निर्माण का अधिकार है। स्मरणीय है कि विचार-स्वात त्र्य एव समुदाय के अधिकार को समाज-हित मे सीमित किया जा सकता है लेकिन उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। व्यक्तियो की भिन प्रकार की इच्छाओं की अभिव्यक्ति विभिन्न समृहा के माध्यम से होती है। अत विभिन्न दबाव समृहों के रूप में हितों के समर्थों के द्वारा वे समाज म लोकत न का निर्माण करते हैं। अत यह कहना कि दबाव समृह राष्ट्रीयता का खण्डित करते हैं. सत्य नहीं है।

दबाव समृहा के दोपा को दूर करने के लिए उन पर सावजनिक निय त्रण की आवश्यक्ता होती है। जिससे वे खुले रूप में उचित साधनों का प्रयोग करते हुए अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए काय करें। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि दवाव-समूहों हारा अपने सदस्यों के प्रति उचित व्यवहार किया जाता है। इस हेत्—

 उनके सगठन व्यवस्थित एवं अधिकारी निर्वाचित तथा उनकी अपनी कायकारिणी होती चाहिए।

(2) दवाद समूहो पर विधिक नियानण होना चाहिए जिससे के अधेक्षाकृत अधिक उत्तरदायित्वपूण रीति से उद्देश्य की प्राप्त कर सके। उन्हें अधिक प्रमानशाली बनाने के लिए उनकी व्यापक भी बनाया जाना चाहिए।

(3) दवाब-समूहा को लोकता निक बग से काय करता चाहिए ज्यांत उनक निगय बहुमत पर आधारित होने चाहिए, गुप्त निर्वाचन की व्यवस्था होनी चाहिए, उन्हें अपना आधिक लेखा-जोखा रखना चाहिए और उनकी अवाधनीय गतिविधियों पर प्रतिव प होना चाहिए।

इसकी भी आवश्यकता है कि दवाव-समूह को समाज विरोधी, प्रतिक्रियावादी तया भारत जसे दस की हप्टि से अराष्ट्रीयता एव साम्प्रदायिकता का गढ नहीं होना चाहिए। सामाजिक एवं दबाव समृह के हितों य उचित सन्तुसन एवं व्यवस्था की मारत में अनेक सास्क्रतिक समूह है। विद्या से मैंत्री सम्ब धा वा बढान के लिए उननी स्थापना की गयी है, जसे—मारत-सोवियत, भारत ईरान, मारत-पूर्णास्ताव सप आदि। इस प्रकार के समठनो द्वारा भारतीय नीति को प्रभावित करने का प्रयत्न किया जाता है। साम्प्रदायिक एव धार्मिक सगठन भी देश की नीति को अपने विचारा के अनुरूप प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। व्यावसायिक समूहा म प्रमुख सप हैं शिक्षकों के सप, विस्वविद्यालय शिक्षक सप, भारतीय बार (वकील) एसोसियेसन, मैडिकल एसोसियेशन, अखिल भारतीय के द्वीय सरकारी कमचारियों के विभिन्न सप, रिक्षेत्र कमचारी सुष्ठ पृथव-प्रवत्न सप।

प्रादेशिक सगठन के रूप म जिब बेना' का नाम सिया जा सकता है। गाधी-वादी विचारधारा का देश में प्रचार करने वाले अनेक क्षय हैं। कुछ विश्वविद्यालयों म गाधी बदान नी शिक्षा दो जाती है। विभिन्न गाधीबादी पुरस्कालया। एव चलवा की स्थापना की गायी है। सर्वोदय समाज देश का सबसे बड़ा गाधीबादी सगठन है। अकाली दल, हिंदू महासभा, रिपम्लिकन पार्टी, अनेक मुखलिम दलों को सम्प्रवाधिक समुदायों में सम्मिलत किया जा सकता है। भारतीय ईसाइया का अखिल मारतीय सम, आय प्रतिनिधि समा, सनावन धमरकिणी सभा, धार्मिक सगठनी ने प्रकार हैं। देश म जाति के आधार पर भी जमेक सण पाय जाते हैं, यथा—कायस्य समा, ब्राह्मण समा, जाट समा, बगाली समाज, अग्रवाल समा, वश्य समा एव पायुर दश्य सा आदि। निर्वाचनकाल में सामायत जातिबाद की माधना को बलकर उमारा जाता है।

भारत म ब्यावसायिक एव औद्योगिक हित-समृहो द्वारा शासन के उच्चा विकारिया, विधायका, मित्रयो एव विधि निर्माण समित्रिया को अपने पक्ष म प्रमानित करने का हर सम्मव प्रयत्न किया जाता है। प्राय इन समृहो द्वारा शासन की नीतियों का विश्वेषण निया जाता है। एव उनके दोषा को भी प्रकट करते हैं। प्रमिक समें द्वारा रावन के लिए इंडताल का बहुगास्त्र आये दिन प्रयोग किया जाता है। मानत म दवाव समृहो को स्थिति वेट विटेन एव कनाडा के हित समृहो के अधिक प्रमाव के शासन के वापन समाय है। विभान ववाव समृहो को स्थिति वेट विटेन एव कनाडा के हित समृहो के अधिक समीय है। विभान ववाव समृहो हो स्थिति वेट विटेन एव कनाडा के दिन समृहो के अधिक प्रमाव का उपयोग मित्रपण्डल को प्रमावित करते की व्यक्ता अधिक स्थापित कर एक जिल्ला के प्रमाव का उपयोग मित्रपण्डल को प्रमावित करते में किया जाता है। अनेक व्यापन कि हितों ने नई दिल्ली एव राज्यों की राजधानिया से अपने कार्यालय स्थापित कर रहे है। उच्च वेतनधारी कमचारियों के माध्यम से वे मित्रयो एव उच्चाधिकारिया सं सम्यक करके द्वारान की नीति को नियान्तित करने का प्रयत्न करते है। दवाव-समृहा के द्वारा मारत म द्वारान की नीति को प्रमावित करने की रीति का वडी दो प्रताप्तक विकास हो रहा है। हा

निष्कष

दबाद समुहो का आधुनिक लोकता त्रिक समाजा म महत्वपूण स्थान है।

उनको 'अहस्य सरकार', 'विधानमण्डल के पीछे विधानमण्डल', 'अज्ञात साम्राज्य' एव 'सह-सरकार' की सजाएँ दी जाती हैं। इन दवाव समूहो द्वारा अपने उद्देश्य पूर्ति के हर साधन, उचित एव अनुचित भ्रष्ट साधना, रिश्वत, स्त्रियो, घनादि का अपने हित साधन के लिए प्रयोग किया जाता है। समाज में विभिन्न वर्गों एवं हिता की विद्धि के फल स्वरूप दबाव या हित समुहो का विकास स्वामानिक एव वाछनीय है। लॉबीइग की आज अनचित मानना समय के अनुरूप नहीं है। दवाव-समहा के द्वारा प्रयोग किये जाने वाले अनुचित तरीका के प्रति आपत्ति का होना स्वामाविक है। पर तु प्रश्न है कि वे ऐसा क्यो करते है ? उनके द्वारा अनुचित, अध्ट एव उत्कीच के साधनी का प्रयोग क्या किया जाता है ? क्या इसका यह अथ नहीं है कि हित समृहों को नियनित एव स्धारने की आवश्यकता है। यह कहा जाता है कि दवाव समृहो द्वारा व्यक्तिगत हितो को प्रश्रय देकर राष्ट्र की आत्मा को खण्डित किया जाता है। क्या यह आराप सत्य है ? लोकतान का महत्वपूण सिद्धात विचार स्वातात्र्य एवं समुदाय निर्माण का अधिकार है। स्मरणीय है कि विचार-स्वात व्य एव समुदाय के अधिकार को समाज-हित मे सीमित किया जा सकता है लेकिन उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। व्यक्तियो की मिन प्रकार की इच्छाओं की अभिव्यक्ति विभिन्न समुहों के माध्यम से होती है। अत विमान दवाव समृहों के रूप में हितों के संघर्षों के द्वारा वे समाज में लोकतान का निर्माण करते हैं। अत यह कहना कि दबाव समृह राष्ट्रीयता को खण्डत करते हैं. सत्य नहीं है ।

दबाब समूहा के दोपा को दूर करने के लिए उन पर सावजनिक निय पण की आबहयकता होती है। जिससे वे खुले रूप मे उचित साधनो का प्रयोग करते हुए अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए काय करें। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि दबाब-समूहो द्वारा अपने सदस्या के प्रति उचित व्यवहार किया जाता है। इस हेत्—

(1) उनके सगठन व्यवस्थित एवं अधिकारी निर्वाचित तथा उनकी अपनी कावकारिणी होनी चाहिए।

(2) दवाव समूहो पर विधिक नियात्रण होना चाहिए जिसस वे अपेक्षाकृत अविक उत्तरदायित्वपूण रीति से उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। उन्हें अधिक प्रमावशासी बनाने के लिए उनकी व्यापक भी बनाया जाना चाहिए।

(3) दबाव समूहो को लोकता जिक ब्ल से काय करना चाहिए अथात् उनके निणय बहुमत पर आधारित होने चाहिए, गुप्त निर्वाचन की व्यवस्था होनी चाहिए उन्ह जपना आर्थिक लेखा जोखा रखना चाहिए और उनकी अवाछनीय गतिविधिया पर प्रतिब थ होना चाहिए।

इसकी मी आवस्यकता है कि दवाब-समूह को समाज विरोधी, प्रतिक्रियावादी तथा मारत जस देस की दृष्टि से अराष्ट्रीयता एव साम्प्रदायिकता का गढ नहीं हाना चाहिए । सामाजिक एव दवाव समुह के हिता में उचित सन्तुसन एवं व्यवस्था की अवश्यकता है। संयुक्त राज्य अभेरिका म 1946 ई म हित समूहो से सम्बिप्त एक विभेयक (Federal Regulation of Lobbying Act) पारित किया गया था। इसके अनुसार (1) सभी दवाब-समूहों के बैतिनक ऐजेण्टो (Lobbyins) को अपने नाम कायेस म पजीकृत करना आवस्यक है, (2) प्रत्येक एजेण्ट को अपने द्वारा व्यय किय भन का हिसाब रखना चाहिए तथा किन्न कितना मन दिया है इसका विव-रण रखना चाहिए और मा ताबीइग के लिए प्राप्त पन एव उसका विवरण देना चाहिए, तथा (3) अपने निजी सम्ब यो का भी प्रत्येक ऐजेण्ट को विवरण देना चाहिए, तथा (3) अपने निजी सम्ब यो का भी प्रत्येक ऐजेण्ट को विवरण देना पडता है।

डॉ एम जी मुप्ता में के अनुसार बहुलवाद का अर्थ लोकता िमक उप पर सग
ित क्वायत्त एव निर्धारित मायदण्ड के अनुसार आचरण करने वाले दबाव समूझे को
बडावा देना है। यह नम उपयोगितावाद या समूह उपयोगितावाद है जिसकी इकाई
ध्यक्ति न होकर पुण या समूह है। इसमें ध्यक्ति नहीं समूह कच्याण की इकाई होती
है। समूह उपयोगितावाद उप अहस्तकों प विश्वास नहीं करता अपितु सकारायक
राज्य की धारणा म उसकी आस्या है। विकिन दबाव समूहों के सकीण क्षेत्र एव निर्धित
स्वार्थों के प्रति सतक रहना भी आवस्यक है। अधिकाद दवाव समूहों के सकीण क्षेत्र एव निर्धित
स्वार्थों के प्रति सतक रहना भी आवस्यक है। अधिकाद दवाव समूह आर्थिक एव
ध्यादसायिक हितो से सम्यापत होते हैं और अपने हिता के लिए अवधानिक एव
अनुचित साथनों का प्रयोग करने भे नहीं हिवचत्त है। अत उहें ध्यवस्थित एव
नियात्र सर की आवस्यकता है। आधुनिक समय य दवाव समूह आकतात के
विरोधी सहीं है।

मौलिक श्रधिकार [THE FUNDAMENTAL RIGHTS]

प्राय सभी आधुनिक सविधानों में मौलिक अधिकारों का उल्लेख एक अनि वाय विशेषता मानी जाती है। इससे शासन की निरकुशता पर प्रतिबाध लग जाता है। अधिकार से तात्पय व्यक्तिया को समाज एव राज्य द्वारा प्रदत्त कुछ ऐसी स्वि-घाओं से है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की हृष्टि से आवश्यक है। अग्रेज विद्वान मक्कन (MacCan) के अनुसार, 'अधिकार सामाजिक कल्याण की कुछ लामदायक परिस्थितिया हैं जो नागरिक के यथाध विकास के लिए अनिवास है। 'लास्की ने 'अधि कारों को सामाजिक जीवन की उन परिस्थितिया की सज्ञादी है जिनके अमाय मे व्यक्ति का पूण विकास सम्भय नहीं है।"1 अधिकार एवं कतव्य दोनों का जोड़ा है। वे एक ही सिक्के के दा पाइव हैं । हावहाउस² (Hobhouse) के जनुसार, "अधिकार व कतव्य सामाजिक कल्याण की दशाएँ है।" समाज के प्रत्येक सदस्य का इस कल्याण के प्रति दहरा दायित्व है। अधिकार एक माग है तो कत य दूसरी माग है। मेरे अधिकार समाज के सदस्यों पर कतव्य निर्धारित करते हैं और अप सदस्यों के अधिकार मेरे कतव्य को निश्चित करते है। अधिकारो से अय व्यक्ति क नैतिक विकास के लिए आवश्यक सामाजिक परिस्थितियो एवं सुविधाओं से हैं जिनकी चृष्टि समाज द्वारा की जाती है। प्रत्येक काल एव युग में इनके तत्व बदलत रहे हैं। अधिकार समाज की सप्टि हैं पर तु अधिकार के उपयोग के लिए राज्य अनिवास है। राज्य विधि बनाकर प्रत्येक व्यक्ति का क्षेत्र सीमित रखता है। दूसरे शब्दा मे, अधिकारों के प्रयोग के लिए राज्य एक अनिवाय अवस्था है। अत राज्य अधिकारा का विरोधी नहीं होता अपित् सरक्षक है। जब राज्य इनको अस्वीकार कर देता है तो उसके लिए

¹ Lasks A Grammar of Politics, 1941, p 91

² Hobhouse Elements of Social Justice, p 39

सकट उत्प न हो जाता है। अमरिनी भाति, फास की राज्यकाति, रूसी लाल माति एव विभिन्न उपनिवेशा म राष्ट्रीय आ दोलन इसक प्रमाण हैं।

अधिकारो के प्रकार

जापूनिक प्रगतिश्वील देशा में दो प्रकार के अधिकार हाते हैं राजनीतिक अधिकार (Political rights) एवं सामाजिक या नायरिक अधिकार (Civil rights)। राजनीतिक अधिकार का तात्प्य उन अधिकारों से हैं जिनके आधार पर व्यक्तियों को सासन काय में मांग लेन का अवसर प्राप्त होता है। लोकता प्रक देशों में यह अधिकार बिता किसी भेदमाव के सभी नागरिका पायत होता हैं। इन अधिकारों से तात्प्य मत देने निर्वाचित होने एवं सासन मं पद ग्रहण करने के अधिकार से हैं। इन अधिकारों के तात्प्य मत देने निर्वाचित होने एवं सासन मंपद ग्रहण करने के अधिकार से हैं। इन अधिकारों का प्रयोग सामायत अनिवाय नहीं हैं परंतु कुछ राज्या मंराजनीतिक कर्य या अर्थात मतवाल एवं सनिक सेवा को अनिवाय कर दिया गया है।

राजनीतिक अधिकारा के अतिरिक्त अनेक सामाजिक या नागरिक अधिकार व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। केवल राजनीतिक अधिकार ही व्यक्ति के व्यक्तित्व के दिकास के लिए आवश्यक नहीं हैं। प्रमुख सामाजिक अधिकार है जीवन, वयक्तिक स्वतात्रता धर्म एव अन्त करण की स्वतात्रता, शिक्षा, सम्पत्ति, विचार लेखन भाषण की स्वत त्रता, समा बनाने, सविदा करने, समानता एव राज्य के विरोध के अधिकार । जीवन के सामाजिक, आधिक, सास्कृतिक, धार्मिक एवं पारिवारिक पक्षा के विकास के लिए उपरोक्त अधिकारों का तीव समयन किया गया है। इन अधिकारों में मानवीय सभ्यता के विकास के साथ साथ विद्व होती रही है। राजनीतिक एव सामाजिक अधिकारा क मध्य मे कोइ विभाजक रेखा नहीं खीची जा सकती । दोना भ यो याश्रित है। एक के विना दूसरे का प्रयोग सम्मव नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने 1946 में श्रीमती फ्रॉक्सिन डी क्जवेल्ट के नेवृत्व म मानवीय अधिकार आयोग की स्थापना की थी। इस आयोग द्वारा प्रस्तावित मौलिक अधिकारो को मयुक्त राष्ट्र सघ की सामा य समा (General Assembly) ने व्यक्तियो के सावमीम अधिकारा (Universal Declaration of Rights of Men) के रूप मे 10 दिसम्बर, 1948 को स्वीकार किया था। इस घोषणा म निम्नलिखित मानवीय अधिकारों को मौलिक माना गया है जा प्रत्यक व्यक्ति को विना किसी भेदमान के प्राप्त होने चाहिए ।

"आवागमन एव आवास की स्वत त्रता, आवय एव राष्ट्रीयता प्राप्त करन की स्वत त्रता, बि तन, अ त करण, घम, विचार और अभिव्यक्ति नी स्वत त्रता, विवाह और परिवार की स्वत त्रता विनतपुर्वक मध बनाने की स्वत त्रता, दिश के श्रासन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रीति सं माव कैने का अधिकार, सम्मत्ति का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, निश्चित जीवन स्तर एव शिक्षा क अधिकार काम की जीवत परिस्मितियाँ, आराम और अवकाश का अधिकार आदि ।'

मौलिक अधिकारा की इस घोषणा का विशेष महत्व है। यद्यपि इसे किया न्वित करन के लिए आवश्यक विधिक शक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ को प्राप्त नहीं है परातु यह सत्य है कि इन अधिकारा को समस्त देशा द्वारा स्वीकार किये जान पर ही सच्चे मानव परिवार का उदय होगा। इन्ह स्वीकार करने वाले राज्यो द्वारा इनको अपने यहाँ किया िवत किया गया है। उपरोक्त सभी अधिकारो म उचित जीवन-स्तर के अधिकार (अनुब्छेद 25) का भी उल्लेख है। यह नागरिका के व्यक्तित्व के विकास के लिए भौतिक आधार प्रदान करता है। इस अधिकार के अभाव म अप अधिकारो का कोई व्यायहारिक महत्व नही रहता है। लेकिन यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि यदि विचार, भाषण, धम, समा, सघ, परिवार, जादि के अधिकारों की स्वीकार कर लिया जाता है तो जीवन स्तर का निर्माण देर अवेर से हो ही जाता है। सर्वाधिकारी राज्य म युनतम जीवन स्तर स्थापित किया जा सकता है पर तु इससे जीवन की इकाई के रूप मे ध्यक्ति का निर्माण नहीं किया जा सकता। केवल स्वस्थ शरीर ही व्यक्तित्व का विकास नही है। हीनता, दायता मय आगका, अविश्वास से पीडित व्यक्ति का व्यक्तित्व कृष्ठित एव दलित होता है। व्यक्ति के नतिक व्यक्तित्व के निर्माण के लिए उपरोक्त स्वत नताएँ आवश्यक हैं एवं यही उचित जीवन-स्तर का आधार बन सकती है। परात उचित जीवन-स्तर का अधिकार उपेक्षणीय नहीं है। व्यक्ति के मितक एव भौतिक दोनो ही प्रकार के विकास की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय अधिकारा की घोषणा ने इस पर बल दिया गया है। इन सभी अधिकारा का पालन सम्रक्त राष्ट्र सघ के सदस्य राज्यो द्वारा समान रूप स नहीं किया जा रहा है। दक्षिणी अफ्रीकान अपने यहारणभेद नीति का अनुगमन कर रखा है। अनेक बार महासभा ने निदा प्रस्ताव पारित किय पर तु उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ है अपितु दक्षिणी अफीका सयुक्त राष्ट्र सम से इस कारण स्वत ही पृथक हो गया है।

क्या अधिकारो का सविधान में उल्लेख होना चाहिए?

मौलिक अधिकारा को सविधान म लिपिबढ कियो जाना चाहिए या नहीं, एक विवादास्पद प्रश्न है। ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफीका स्विट परलण्ड में प्रथक मीलिक अधिकारा सम्बन्धी कोई व्यवस्था नहीं है। ततीम फ़्ल गणराज्य में भी मीलिक अधिकारा सम्बन्धी कोई व्यवस्था नहीं है। ततीम फ़्ल गणराज्य में भी मीलिक अधिकारों को व्यवस्था नहीं थी। विकन भीलिक अधिकारों को विधान में स्पष्ट रूप के उल्लिखित करना एक सामा य प्रवित्त है। समुक्त राज्य अमेरिका के सविधान में मीलिक अधि कारों का उल्लेख है। सारतवप (1951), नवीन जापानी सविधान, मावियत (स्टालिन) सविधान (1936) वर्षी सविधान पाक सविधान (1956) में मीलिक अधिकारों का उल्लेख है। इसके पूर्व 1919 ई के वीमर जमन सविधान एव 1922 ई एवं 1936 ई के आयरिस सविधानों म भी मीलिक अधिकारा का स्पट्ट उल्लख विदान पार ।

924 । आधुनिक शासनस व

ब्रिटिश राजनीतिज्ञ एव सविधानशास्त्रियो का मत है कि लिखित मौलिक अधिकारों का कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है। केवल घोषणा मात्र से मौलिक अधि कार नहीं मिलते है। यह मत बहुत कुछ ठीक भी है। ब्रिटेन म नागरिका को सबसे अधिक स्वता त्रता प्राप्त है यद्यपि वहाँ अधिकार लिपिबद्ध नहीं है। ब्रिटिश इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि स्वत त्रताओं को प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश जनता को निरकुश राजाओ के विरुद्ध दीधकाल तक समय करना पढा और इस सघप के अत्तगत उसे सम्पत्ति और स्वतन्त्रता की विल देनी पढ़ी है । इसके अति रिक्त ब्रिटेन को वतमान स्थिति तक पहुँचने में एक लम्बा समय लगा है। ससद ने महत्वपूर्ण विधेयको के माध्यम म व्यक्ति की स्वत त्रता की रक्षा सम्बंधी व्यवस्माएँ की हैं। उदाहरणाथ 1215 ई का मैगना कार्टी, 1629 ई का अधिकार आवेदन-पत्र, 1679 ई का अधिकार पत्र (Bill of Rights) एव वादी प्रस्यक्षीकरण अधि नियम । अधिकार क लिए ब्रिटिश जनता ने जो समय किया या वह निरक्श राजाओं के प्रति था, न कि ससद के प्रति । त्रिटिश जनता ने इस घारणा को कभी स्वीकार नहीं किया है कि विधानमण्डल द्वारा भी व्यक्ति की स्वत प्रदाशों को सीमित किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि ब्रिटेन से ससद की सम्प्रमता है। इसके अतिरिक्त लिखित मौलिक अधिकार जनता म ऐसी आशाआ की जम देता है जिनके पूर्ण न होने पर जन अस तोप पनवता है।

मीलिक अधिकारो को सिंबधान के अत्तरात लिपियद करने के समयको का यह तक है कि इससे मीलिक अधिकारो को एक विवोध प्रकार की पवित्रता प्राप्त हो जाती है और विधि निर्माताओं द्वारा सहज हो उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। वे सासन के लिए एक स्थायी स्मृति के रूप में कांग्र करते हैं। मीलिक अधिकारो एवं स्वताताओं के उरुलेख के कारण राज्य का कांग्रेसी सीपित हो चाता है। तर्वाता तो तिक देशा में मीलिक अधिकारो वा उरुलेख सहस्तीय है। मयुक्त राज्य कमें रिका के सविधान निर्माताओं ने विदेश परस्पर। का अनुसमन नहीं किया है। उनका विधायी सम्प्रमुता म विश्वास नहीं था। अपितु मौलिक अधिकारा की रक्षा का वाधिस्व यायपालिका को सीप दिया है। उनेरिकी इप्टिकोण के अनुसार मौलिक अधिकार राजनीतिक विधान के परे हैं। उन्ह विधान का विषय नहीं बनाया जा सकता और न उहे विधानमण्डल एक युक्त एवं मनोदसा पर ही छोड़ा जा सकता के अनुसार कामपालिका एक य्वयदस्थायिका से मौलिक अधिकारों की रक्षा का समिता कामपालिका एक युक्त एक सनोदस्था पर ही छोड़ा जा सकता है। उनके अनुसार कामपालिका एक य्वयदस्थायिका से मौलिक अधिकारों की रक्षा का सियस यायपालिका का है।

विभिन्न देशो मे मौलिक अधिकार एव नागरिक स्वतन्त्रताएँ ग्रेट विटेन मे नागरिक स्वतन्त्रताएँ

ग्रेट ग्निटेन में भारत, समुक्त राज्य बमेरिका बादि देशा की मौति स्पष्ट रूप से अधिकारी एव स्वत त्रताओं की सविधान म पोई लिखित व्यवस्था नहीं है। पर तु बिटिरा जनता को मारत एव संयुक्त राज्य अमिरका की मौति ही नागरिक स्वत नताएँ प्राप्त हैं । मतदान एव राजनीतिक पद बहुण करन के महत्वपूण राजनीतिक अधकार न्निट्य नागरिका नो भी प्राप्त हूं। स्मरणीय है कि ब्रिटेन मे ससदीय सम्प्रमुता का
सिद्धात मान्य है, न्निट्य सिवधान विकास का परिणाम हैतथा वह प्रधानत अलिखित
है। अत न्यायालया को ससदीय विधि को अवैधानिक घोषित करने की शक्ति प्राप्त
नहीं है। ऐसी स्थित में लिखित सविधान प्रधान देवा को जनता को यह स चेह होना
स्वामाविक है कि ब्रिटिश ससद विधियाँ पारित करके नागरिक स्वत नताओ को
सीमित कर सकती है। लेकिन स्थित इसके विषरीत है। ब्रिटिश नागरिक विश्व मे
सबसे अधिक स्वत नताओ का उपमोग करते हैं।

ब्रिटिश जनता को कुछ अधिकार तो ससदीय विधिया द्वारा प्राप्त है। 1679 ई म बादी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा बादी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त हुआ था। 1689 ई के अधिकार पत्र (Bill of Rights) द्वारा बादी प्रत्यक्षीकरण का पून आद्यासन दिया गया । इसके अतिरिक्त याचिका का अधिकार, अत्यधिक जुर्माना एव अमानुपिक दण्ड से रक्षा, स्वतात निर्वाचन एव अपराधी घोषित किये जाने के पूव एव जब्ती से सुरक्षा सम्बाधी अधिकार ब्रिटिश नागरिको का सामाय कानून (Com mon Law) के आधार पर प्राप्त है। 'कॉमन ला' से ताल्पय रीति रिवाज आधित उन वधानिक नियमो से है जिनका निर्माण ससद अथवा सम्राट द्वारा नही किया गया है, अपित जो यायालया द्वारा मायता प्राप्त हैं। अब कॉमन लॉ यायालय द्वारा स्वीकृत रीति रिवाज हैं। सामा य विधि का नॉमन काल के पश्चात विकास हुआ है। भाषण एव प्रेस, समा, समुदाय, धम एव निजी सम्पत्ति सम्बन्धी स्वत नताओ का आधार कॉमन लॉ हैं। ये स्वतात्रताएँ सामाय विधि की इस धारणा पर आधारित है कि मागरिक इनका उपमाग उस समय तक कर सकता है जब तक कि वे किसी कानन की भग नहीं करत या नागरिका के समान अधिकारा को आधात नहीं पहचाते हैं। उदा-हरण के लिए, भाषण की स्वतात्रता का कोई लिखित आधार नहीं है परात वह उस समय तक माय है जब तक कि स्पष्ट रूप से उसका निपेध नहीं किया जाता है। बिटेन मे दोपारोपण, राजद्रोह आदि से सम्बन्धित विभियों के द्वारा मापण की स्वतात्रता सीमित है।

इसके अतिरिक्त ब्रिटेन में स्वत नताओं का बाबार-विधि का शासन एवं जनमत (Public Opinion) है। विधि के शासन का अय है (1) निरकुश शासन का अगात, (2) विधि के समक्ष समानता, एवं (3) सर्वेशानिक सिद्धा त यायिक निणया के परिणाम हैं। निरकुश शासन के अभाव का अय यह है कि शासन जन-सहमति पर आधारित है अर्थों देश में ससदीय शासन हैं और राजा के परमाधिकारों (Prero gratives) को सीमित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त शासन को व्यक्ति के विवार, स्वाया, सामाजिक आदतों बादि के सम्बंध म कम से कम

करना चाहिए। विधिक समानता से तात्पय यह है कि विसी मी व्यक्ति के साथ कोई भेदमाव न हो और समी एक ही विधि के अधीन होने चाहिए। विधि के शासन का अय यह है कि व्यक्तियों के अधिकारों की व्याख्या यायालयों द्वारा कॉमन लों के आधार पर की जाती है और अधिकारो के अनुसार एव अनुरूप ब्रिटिश ससद व यायालय काय करते है तथा शासन का कायक्षेत्र भी इन नागरिक स्वत त-ताओं के अनुसार निर्धारित किया जाता है। अत इगलण्ड मं सर्विधान की जडे नागरिक अधिकारा मे है। विधि के शासन के अनुसार सम्पूण सविधान व्यक्ति के मौलिक अधिकारा के अनुरूप है। विधि के शासन के सिद्धात के अधीन ब्रिटिश जनो को निम्न स्वत नताएँ प्राप्त है वैयक्तिक स्वत नता का अधिकार, किसी भी ब्यक्ति को उस समय तक व दी नहीं बनाया जा सकता और न ही हिरासत म लिया जासकता है जब तक कि उसने किसी विधि को निश्चित रूप से भग न किया हो, यायालय द्वारा अपराधी सिद्ध होने पर ही उसे दण्ड दिया जा सकता है, याया लय की कायवाही गुप्त नहीं हो सकती तथा अभियुक्त की वकील के द्वारा अपनी सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। अपराध प्रमाणित करने का भार अभियोग पक्ष पर होता है। फीजदारी मुकदमो के निणय जूरी के सहयोग द्वारा ही दिये जाते हैं एव अभियुक्त को उच्च यायालयो म अपील का अधिकार प्राप्त है। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य व्यक्तिकी स्वेच्छाचारिता से रक्षा करना है। प्रत्येक अग्रेज का घर उसका दग माना जाता है।

यह प्रश्न सहज ही उत्पन होता है कि ब्रिटेन मे मौलिक अधिकारो के अलि-खित होने एव ससदीय सम्प्रमुता के सिद्धात के माय होने के कारण क्या ब्रिटिश जनो के मौलिक अधिकारा का हनन ससद द्वारा किया जाता है ? इस सम्बंध मे ससद पर क्या अकुश या निय त्रण हैं ? सिद्धा तत ससद अधिकारो को सीमित, निलम्बित एव पूणत समान्त करने की विधिक शक्ति रखती है। सकट काल म ब्रिटिश ससद ने स्वत त्रताक्षा की सीमित करन वाली अनेक विधिया पारित की हैं, उदाह-रणाथ-दो विश्वयुद्धा के मध्य पारित साम्राज्य सुरक्षा अधिनियम । 1914-15 ई के साम्राज्य सरक्षा व्यक्तियम (Defence of the Realm Act of 1914 15) एव 1939 ई के सकटकालीन शक्ति अधिनियम (Emergency Powers Defence Act. 1939) द्वारा व्यक्तिया के भाषण, सभा एव प्रेस की स्वत त्रवाला पर कठोर प्रतिबाध लगाये गय थे। लेकिन सकट-काल की समाप्ति क पश्चात इस प्रकार क प्रतिबाध विटिश जनता को स्वीकाय नहीं हैं। इसका कारण देश की परम्परा एव जनता में व्याप्त सामा य राजनीतिक चेतना है । जनता शान्ति काल में स्वता नताओं पर इस प्रकार के प्रतिवाधों के विरुद्ध रहती है । ब्रिटिश समाज म यह विचार सिन्त्य है कि ससद स्वय विधि के शासन के अधीन है। अत ब्रिटिश ससद ऐसी किसी विधि का निर्माण नहीं करती है जो नागरिक स्वत यताबा को सीमित करती हो ।

ब्रिटेन में विधियों का उद्देश्य स्वतात्रताओं को सीमित करना नहीं अपितु उनका प्रसार करना होता है।

'विधि के शासन' का ब्रिटेन म नतमान काल मे ह्वास हो रहा है । इससे नागरिक स्वत नताओं के ह्वास की सम्मावना बढ़ी है। कभी कभी ऐसी परिस्थितिया उत्पत्र हो जाती हैं कि विधि के शासन को भी सीमित करना पडता है। डॉ गुप्ता³ ने सोबलिन विवाद (Soblen's Case) का प्रमाणस्वरूप उल्लेख किया है । इस मामले में डॉ रॉबट सोवलिन के देश से निष्कासन (deportation) सम्बाधी गृहमात्री के आदेश को "यायालय द्वारा मा"य ठहराया गया था । ब्रिटेन मे नागरिक स्वता उताएँ सदियों के यायिक निणयों एवं यायाधीकों की निप्पक्षता, निर्मीकता एवं ईमानदारी का परिणाम हैं। उपरोक्त विवाद म 'यायासय का निजय औपचारिक रूप में (tech nically) सही हो सकता है पर तु इससे यह भी स्पष्ट है कि ब्रिटिश यायालय किस सीमा तक कायपालिका की नीतियों का ध्यान रखते हैं। विधि के शासन को इस प्रवित्त से खतरा है। यही नहीं शासन की बढ़ती हुई शक्ति प्रवत्त विधि निर्माण एव प्रशासकीय यागालयो की स्थापना के फलस्वरूप मित्रयो को वयक्तिक स्वत प्रताओ के मामला म हस्तक्षेप के अनियातित अवसर प्राप्त हो गये हैं। यह ठीक है कि काय-पालिका द्वारा शक्तियों का प्रयोग मनमाने दम स नहीं किया जाना चाहिए परत् यह भी एक कट सत्य है कि "याय आप्त करने के लिए आवश्यक मृख्य चुकाने की क्षमता भी सामा य नागरिक म नहीं होती है। इन सब आशका जो एव सम्मावनाओं से ब्रिटेन में नागरिक स्वत नताओं का रक्षक वहां का प्रबुद्ध एवं जागरूक जनमत है। निर्वाचक, दनिक समाचार पन एव जनमत ससद एवं सरकार के विभिन्न जगा की अपनी सीमा मे रहने के लिए बाध्य करते है। ब्रिटिश शासन जनता क प्रति उत्तर-दापित्व के सिद्धात पर आधारित है। अत कायपालिका सदव ही जनमत का ध्यान रखती है। इसके अतिरिक्त 'विधि के शासन' के सिद्धाती को यायालय मायता प्रदान करते हैं एव वे व्यक्तिया की स्वत नताओ एव अधिकारा के रक्षक के रूप म कायशील रहते हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने मौतिक अधिकार

सपुनत राज्य अमेरिका के सर्विधान के मूल प्रारूप म जिसे राज्या को स्वीकृति के लिए भेजा गया या, नाथरिकों के अधिकार पत्र का समावेश नहीं था। अत पढ़िक हेतरी, रिचाइ हेतरी ली एव अय कुछ देवामनतो न प्रस्तावित सर्विधान का इस आधार पर तीव विरोध किया कि उसम अधिकार पत्र (Bill of Rights) का स्वार वेदा नहीं है। उनका तक या कि अधिकार-यत्र के अभाव म स्विधान जनता की स्वत नताओं की इंग्टि से खतरनाक सिद्ध हो सकता है। एक्टरिक्टर—मुख्यादिन

³ M G Gupta Modern Government Theory & Practice, 1967 P. 5

ने इस पर नवीन सासन के समित्र होने पर अधिकार-पन के समावेश का वचन दिया। फलस्वरूप नवीन सासन द्वारा अमेरिकी सविधान म प्रथम दस सशोधनो के द्वारा मौलिक अधिकारा का समावेश किया गया। प्रथम आठ सशोधनो मे जिन स्वत-त्रताओं का उल्लेख किया गया है वे इस प्रकार है

(1) प्रत्यक व्यक्ति को धम, नापण, तेख, समा एव प्राथना करने की स्यतन्त्रता प्रदान की गयी और इनका विरोध या इन्हें सीमित या निषिद्ध करने वाली विधियों के निर्माण से काग्रस को विचल कर दिया गया। (प्रयम संशोधन)

(2) प्रत्येक व्यक्ति को शस्त्र धारण करने का अधिकार प्रदान किया गया। (प्रथम सरोधन)

(3) शांति काल में गहस्वामी की अनुमृति के विना किसी घर म सिनक ठहराने पर प्रतिवाध लगा दिया गया और युद्ध-काल म मी विधि द्वारा निर्धारित रीति के विपरीत किसी घर में सिनको को नहीं ठहराया जा सकता है। (द्वितीय संशोधन)

(4) प्रत्येक व्यक्ति को अपन जीवन, सन्यक्ति एव निवास स्थान की सुरक्षा प्राप्त है एव किसी की अनुचित रीति से तलाशी नही ली जा सकती और न उसकी सम्यक्ति को ही जकत किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के विरुद्ध आदेश-वारण्ड उचित कारण के बिता, जिसका समयन शापय या इडतापुवक नही किया गया हो, जारी नहीं क्यिया सकता। वारण्ड में तलाशी के स्थान, व्यक्ति एव वस्तुएँ जिन्हे ब वी बनाया जाना है या जिन्ह जकत करना है, का स्थप्ट उल्लेख होना चाहिए। (सतीय सशोधन)

(5) जूरी द्वारा हत्या या ऐस ही अन्य गम्भीर अपराधों के निणय किये जाने की व्यवस्था है। शांति या युद्धकालीन शनिक एवं नी सनिक अपराध इस नियम के अपवाद है। किसी भी व्यक्ति की एक ही अपराध के लिए दो बार दिण्डत नहीं किया जा सकता है और न किसी व्यक्ति की फौजदारी विवादों म अपने विरुद्ध साक्ष्य देने कें लिए ही बाध्य किया जा सकता है।

(6) किसी भी व्यक्ति को विधि को उचित प्रक्रियां (due process of law) के बिना जीवन, स्वतानता एव सम्पत्ति से बचित मही किया जा सकता। निजी सम्पत्ति को बिना क्षातिपूर्ति के सावजनिक उपयोग के लिए नही लिया जा सकता। है। फीजदारी विवादो म अभिमुक्त को यह अधिकार प्राप्त है कि विवाद का निजय रीमिता पूत्रक किया जाना चाहिए तथा खुती बदालत में निजयत जूरी के अधीन मुनद्दी के सुनवाई होनी खाहिए। अभिमुक्त को अपनी पुत्त द के बकील को सहायता प्राप्त परन की सुनवाई होनी खाहिए। अभिमुक्त को अपनी पुत्त द के बकील को सहायता प्राप्त परन की सुनवाई होनी खाहिए। अभिमुक्त को प्रचान की जाती है तथा उसके सुनवाई विवाद में सुनवाई वाह हो। (सुरुवाई सवीपन)

(7) सामाय विधि सम्बाधी ऐस विवाद जिनका सम्बाध 20 डालर से

अधिक होता है, जुरी के विचाराधीन होत हैं। (सातवा संशोधन)

(8) किसी अभियुक्त से न तो अत्यधिक नमानत मागी जा सकती है और न उस पर अत्यधिक जुमाना ही किया जा सकता है। उसे कूर एव असाधारण दण्ड भी नही दिया जा सकता। (आठवा सशोधन)

(9) यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रथम बाठ सशोधनों में उल्लिखित अधिकारों का अर्थ यह नहीं है कि अमेरिकी नागरिकों को अय अधिकार प्राप्त नहीं हैं। 10वें ससोचन द्वारा यह व्यवस्या की गयी कि जो अधिकार सधीय एवं राज्यों की सरकारों को नहीं दिये गये हैं वे सब राज्यों या व्यक्तियों के पास सुरक्षित हैं।

उपरोक्त अधिकारों के अतिरिक्त मूल सर्विधान म निम्न अधिकारों का भी उन्लेख है

(1) ब दी प्रत्यक्षीकरण सम्ब धी आदेश का अधिकार सविधान द्वारा प्रदत्त है और इसे केवल विद्रोह या आक्रमण काल में ही सावजनिक हित में निलम्बित किया जा सकता है। (अनुष्केद 192)

(2) ऐसी कोई विधि जिसके अतगत बिना मुकहमा चलाये फासी की सजा दी जा सके (Bill of Attainder या ex post facto Law), पारित नहीं की जा

सकती है। (अनुच्छेद 193)

(3) सयुक्त राज्य अमरिका में कोई सामाती (Nobality) पद किसी को प्रदान नहीं किया जा सकता और न कोई अमेरिकी पदायिकारी किसी राजा या विदेशी राज्य से काग्रेस की सहमति के बिना कोई सम्मानसूचक उपाधि ही ग्रहण कर सकता है। (अनुच्छेद 198)

समीक्षा—सिवधान म उल्लिखित विषयों के सम्बंध य काग्रेस की विधि निर्माण शक्ति पर उपरोक्त उल्लिखित अधिकार प्रतिबंध क रूप में है। काँग्रेस ऐसी किसी विधि का निर्माण नहीं कर सकती जो इन अधिकारों का अदिक्रमण करती हो। समी राज्यों में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त हैं। 14वें ससी पाज्यों में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त हैं। 14वें ससी पाज्यों के कांग्रों से भी की गयी है और इस प्रकार ये अधिकार एक ऐसा क्षेत्र हैं जिसका कि कोई सासन विधिक हिन्द से उल्लिखन नहीं कर सकता। अधिकारां की रक्षा का दायित्व सर्वोच्च यायालय पर है। व्यक्ति की रक्षा की हिन्द से अधि कारों की सीमाएँ औपचारिक रूप से सुनिश्चित हैं परन्तु इनको मी व्यावहारिक सीमाएँ हैं। उदाहरण के लिए मामली के बीघ फैसले की व्यवस्था है पर तु विधि के कारण विलम्ब सम्बंधी सम्मावना की उपेक्षा नहीं को जा सकती है, विद्रोह एव आक-मणकाल में वर्दी प्रत्यक्षीकरण को सावजनिक हित म नित्यन्वन की व्यवस्था है, पूरी द्वारा विचार केवल सधीय यायालयों म ही सम्बंध है व्यक्ति राज्य-न्यायालया म अधि-

⁴ आठवाँ सशोधन ।

काम मामलो पर विचार होता है। इस सम्ब घ में सविधान केवल यह प्रत्याभृति देता है कि राज्य 'यायालयों में 'विधि की उचित प्रक्रिया' का पालन किया जायेगा। सर्वोच्च 'यायालय के अनुसार दीवानी एव फीजदारी मामला में विधि की उचित प्रत्या के अधीन जूरी व्यवस्था आवश्यक नहीं है। 1945 ई के पश्चात मैकार्यी काल में अमें रिका में नागरिक स्वतंत्रताएँ पर्याप्त कम हो गयी थो और एक सर्वाधिकारी वातावरण उस्प नहीं में या था। है

अमेरिकी नागरिको के अधिकारो का आधार इगलण्ड का मैगना कार्टी, अधि कारों का आवेदन पत्र (1629 ई) एवं 1689 ई का अधिकार पत्र है। इन अधि-कारों के द्वारा नागरिकों की शासन से रक्षा की गयी है। 20वी शताब्दी में स्थिति वदल चुकी है। 1930 ई के दशक की विश्वव्यापी मादी के फलस्वरूप अमेरिका मे वेरोजगारी अत्यधिक बढ गयी थी। ब्यक्ति काम करने के लिए तयार था पर काम पाना कठिन था । मुक्त ब्यापार नीति म अमेरिकावासिया का विश्वास हिल गया था । ऐसे ही समय राष्ट्रपति केंकलिन डी रूजवेल्ट ने युडीस कायक्रम क्रियान्वित किया था जो तत्कालीन समस्याओ था एक व्यावहारिक समाधान था । इस कायक्रम के आत-गत कपका श्रमिको बादि के सम्ब व मे अनेक विधियो का निर्माण किया गया था। उदाहरणाथ, 1933 ई के एक अधिनियम (Agricultural Adjustment Act) के द्वारा कृषि के उत्पादन मध्यो भ वृद्धि कर दी गयी थी। इस अधिनियम की सर्वोच्च "यायालय हारा अवैधानिक घोषित करने पर काग्रेस ने 1938 ई मे एक नवीन अधि नियम पारित किया था। 1935 ई में काम विकास प्रशासन (Works Progress Administration) की स्थापना की गयी थी । सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (1935) द्वारा अभाव एव निधनता से विभिन्न स्तरो पर सुरक्षा की व्यवस्था की गयी। आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रो म पूडील कायक्रम के अधीन स तोपजनक विद्व हुई थी। अमेरिका मे राज्य के कायक्षेत्र में विद्ध के साथ-साथ व्यक्ति के आधिक मामली मे उसकी सुरक्षा की हिन्द से राज्य का हस्तक्षेप बढ गया है।

हितीय विश्वयुद्ध काल में व्यक्तित स्वत नताएँ और अधिक सीमित हुई हैं। नाजी खतरे का सामना करने के लिए काग्नेस ने एक विधि (Smith Act, 1940) पारित की भी। इसके अधीन हिसा हारा सासन को बदलना एस तसम्बन्धी साठनों को अर्थन पोधित कर दिया गया था। साम्यवादिया को मुख साजनिक करों के कारण वय किंक स्वत नता और सीमित की गयी थी। साम्यवादिया को मुख साजनिक करों किए अयोग्य धाया। अनेक राज्य विधिया हारा पढ्य नकारी (sub versive) साठना की सदस्यता को विधित शासकीय पत्नों के लिए अयोग्य हहरा दिया गया था। काग्नेस की अनेक सरकारी करवादियों को अयोग्य पीधित किया था। खाइको पर इसका सबसे अधिक प्रकार करवादियों को अयोग्य पीधित किया था। शिक्षको पर इसका सबसे अधिक प्रमाय पढ़ा था।

⁵ M G Gupta op cat, p 357

सयुक्त राज्य अमेरिका मे 'विधि के समक्ष' समी नागरिक समान है। लेकिन वहाँ भी यहूदिया एव नीग्रो लोगो के साथ भेदमान किया जाता है। नीग्रो लोगो को अमेरिकी समाज में समानता का स्थान प्राप्त नहीं है। दक्षिणी राज्य में नीग्रो लोगो की हालत आज भी खराब है। सधीय सरकार को इस सम्बन्ध में दक्षिणी राज्यों के विरोध का सामना करना पड़ा है। आज भी अमेरिका में अनेक ऐसे राज्य है जहा नीयो लोगा को क्वेत लोगो के साथ बराबरी का दर्जा नही दिया जाता है। 1962 ई म राप्ट्रपति कैनेडी को मिसीसिपी के राज्य विश्वविद्यालय मे एक नीग्री को प्रवेश दिलाने के लिए विधिक एवं सनिक हस्तक्षेप के माग का अनुसरण करना पडा था।

समक्त राज्य अमेरिका में व्यक्तिगत स्वत प्रताओं का क्षेत्र अ य देशों की अपेक्षा अधिक व्यापक है। 1941 ई मे परम्परागत स्वत प्रताओं की मय एवं अभाव से रक्षा की चर्चा की गयी थी। 1947 ई मे राष्ट्रपति टू.मैन ने नागरिक अधिकार समिति की स्थापना की थी। 1957 ई के नागरिक अधिकार अधिनियम (Civil Rights Act of 1957) के द्वारा 6 सदस्यी समिति को कायपालिका से सम्बद्ध किया गया था। इसका उद्देश्य नागरिक अधिकारा की रक्षा करना था। 1964 ई मे नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया गया और इसके द्वारा नीग्रो जाति के अधिकारो को सुरक्षित किया गया है।

मौतिक अधिकारो का सविधान में उल्लेख अमेरिकी सविधान की प्रमुख देन है एव प्राय सभी परिवर्ती लिखित सविधानो मे इसका अनुसरण किया गया है।

ह्विटज रल पड

स्विट्जरलैण्ड म ग्रेट ब्रिटेन की माति नागरिको के अधिकार-पत्र का अमाव है। सविधान मे अमेरिका एव भारत की माति मौलिक अधिकारो का पथक से उल्लेख नहीं है पर तु सविधान म यत्रतत्र कुछ अधिकारो की व्यवस्था है। कण्टना के सविधानो द्वारा भी नागरिका को अनेक स्वतात्रताएँ एव अधिकार प्रदान किये गय हैं उदाहरणाय, अनुच्छेद 4 मे विधि के समक्ष समानता की प्रत्याभूति दी गयी है। हास हुवर इस अधिकार को सबैधानिक अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है। अनुच्छेद 27 के अनुसार नागरिकों के लिए नि अल्क प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करना कण्टना के शासन का अनिवाय दायित्व है। धम-निरपेक्षता की भी व्यवस्था की गयी है। अनुष्ठेद 31 के अन्तगत व्यापार एव वाणिज्य का अधिकार एव अनुच्छेद 49 के अनुसार सभी नागरिको को अन्त कारण एव धम को स्वतात्रता प्रदान को गयी है। अनुच्छेद 55 प्रेस को स्वत त्रता, अनुच्छेद 56 समुदाय एव सघ के निर्माण एव अनुच्छेद 56 याचिका का अधिकार नागरिको को प्रदान करते हैं। बनुच्छेद 60 के अधीन स्विस नागरिका को स्वतात्रतापूबक किसी भी कैण्टन म निवास करने का विधकार है। इसके अतिरिक्त

⁶ Hans Huber The Federal Constitution of Suitzerland, pp 67

विवाह, निजी सम्पत्ति एव निवास गही सम्बन्धी स्वत त्रता प्राप्त है। वैयक्तिक सम्पति का अधिकार अनुसमनीय है। प्रत्येक व्यक्ति को चारो राष्ट्रीय माधाओं म से अपनी मातुमापा के प्रयोग का अधिकार है। स्विस नागरिकों को कम्यून के शासन म भाग लेने तथा कैण्टनों के अधिकारियों की चनने के अधिकार भी होते हैं । कोई कैण्टन अ प क्ण्टनो के निवासियों के साथ भेदमान नहीं कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की भताधिकार प्राप्त है। मतदाताआ की थाग्यता सघ एवं कैण्टनों के शासन द्वारा निश्चित की जाती है लेकिन इसका यह अब नहीं है कि सब एवं कैंग्टन अपने-अपने क्षेत्र सम्बाधी मतदान व्यवस्था निर्धारित करते हैं। इसके विपरीत, कुछ मामला म कण्टनी सम्बंधी मतदान की योग्यताएँ सधीय शासन निश्चित करता है और कुछ सधीय मामलो मे कैण्टनो के नियमानुसार काय किया जाता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार सधीय सन्ना के निर्वाचन एव जनमत-सग्रह तथा प्रस्तावक (initiative) में भाग लेने का अधिकार प्रत्येक उस 21 वर्षीय स्विस नागरिक को प्राप्त है जो कप्टन के नियमो के अत्तरत नागरिकता से विचित नहीं किया गया है। दो वप (1971 ई) पव तक स्त्रियों को मतदान का अधिकार नहीं या। अनेक बार स्त्रियों को मताधिकार देने के प्रयत्न किये गये परात जनता ने जनमत साउह में इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया था। 1959 ई में स्त्रियों को मताधिकार देने के लिए सबैधानिक संशोधन पारित करने का प्रयत्न किया गमा था परन्त जनता ने 2 1 से उसे अस्वीकृत कर दिया था। बाह "यचेल एव जेनेवा के कैण्टनों की जनता स्त्रिया को मताधिकार दिय जाने के पक्ष में थी अन इन तीन कण्टनों म महिलाओं को मताधिकार प्रदान कर दिया गया था। 1971 ई म स्विटजरलैण्ड म प्रथम बार स्तियो को सताधिकार दिया गया है। मारत एव अमरिकी की माति स्विटजरलैण्ड म भी अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक समीय पापालय (Federal Tribunal) की शरण ले सकता है। यदि किसी विधिया संधीय कामपालिका द्वारा किसी नागरिक के अधिकारा की सीमित किया जाता है तो समीय न्यापालय आवेदन करने पर उ हे निष्प्रमावी घोषित कर सकता है । स्विट्जरलण्ड म प्रत्येक स्वस्य नागरिक क लिए सैनिक मेवा अनिवाय है।

स्थित सिविधान पर उदारवादी विचारधारा का प्रभाव है। व्यक्ति की गरिमा एवं महत्ता शासन व्यवस्था का आधार है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति को अधिक तम सीमा तक स्वतंत्रता प्राप्त है। पाया व्यक्ति के मामलो में कम से कम हस्वतेष करती है। व्यक्ति को आधिक क्षेत्र मं विधानधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। परत्तु 20वी सदी के विचारो एव परिस्थितिया के फलस्वरूप स्वित उदारवाद में कुछ परिवतन आ गया है। 1930 इ की विश्वव्यापी मंदी एव दो विश्वयुद्धों के कारण राजकीय पर अस्म पिक स्थय भार बढ़ गया था। कस्याणकारी राज्य की धारणा एव समिष्टवादी विचार

⁷ Hans Huber, of all p 38

ं उदय एवं विकास के कारण स्विस राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था में कुछ । अनिवायबन गये थे और व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्रों में राज्य द्वारा बहुत इ'ध लगाये गये हैं। वहें औद्योगिक प्रतिष्ठामी (Cartels) के निर्माण के कारण के क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप अनिवाय हो गया था।

स्विट्यर्लंड म निजी सम्पत्ति, समानता, वयक्तिक एव निवास गहा की जा सन्व भी अधिवारा का क्षेत्र सबुक्त राज्य अमेरिका की मौति ही व्यापक है। तियत अपार एवं सम स्वा रीति रिवाजो के उसम निवास करते हैं। विभिन्न भाषा एवं सम सवा रीति रिवाजो के उसम निवास करते हैं। ऐस समाज में मौतिक अधिकारों को व्यवस्था अस्य — माषायी धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक— के लिए मुख्यआधार (sheet r) के रूप में है और लोकत नीय बेतना तथा सहिष्णुता की रक्षा के 'लिए रहें।

। मौलिक अधिकार

1789 ई ने फास के जातिकारियों ने मौलिक अधिकारा की घोषणा की **परणीय है कि फेच का** तिकारी अमेरिकी काति से अत्यधिक प्रमावित थे। हछ नेता जैसे लफायत (Lafayette) ने अमरिकी स्वतायता संप्राम मे माग । प्रया । वह अमेरिकी स्वत त्रताकी घोषणा एव वर्जीनिया (Virginia) के रो की घोषणा से प्रमानित था। दोनो अर्थात् अमेरिको एव फेंच कार्तिकारियो र लाक का प्रमाय था। फांस की फांति के बौद्धिक कायकम के रचिंगताओं र जैफरसन का सम्बंध था। फ्रेंच क्यांतिकारियों के मध्य दो प्रकार के विचार थे, एक बृद्धिवादी विचारक और दूसरे रूसो के समयक । प्रथम विचारधारा ो चितन के अधिक निकट थी। वे विवेक को महत्व दते थे। बुद्धिवादिया का बवेकवादी एवं मानवतावादी था। उन्हें मानव प्रगति एवं उसके विकास मे था। इसो मी निरकुश शासन का विरोधी था परन्त वह विवेक की अपक्षा । नागरिक की मूल प्रवृत्ति की अधिक महत्व देता था। उसके लिए अनुलघनीय रो का महत्व नहीं था। वह व्यक्ति की अपक्षा समिष्टि को महत्व देता है। ग्रमा य इच्छा को सम्प्रमु माना है। रूसो क अनुसार यदि अल्पमत बहुमत से नहीं है तो बहुमत अल्पमत को सहमत या स्वत व होने के लिए बाध्य कर है। वृद्धिवादी विचारको का स्वत त्रता से, जबकि रूसो का राजनीतिक समा-. अधिक सम्ब घ है। फेच अधिकारा के घोषणा पत्र में इन दोनों विचारा के हा समावेश है।

अधिकारों के फेंच घोषण-पत्र की प्रस्तावना म कहा गया है कि "विस्मृति एवं विजित्तिक दुर्भीग्य एवं घासनों के अध्ट होने के कारण हैं।" "समी व्यक्ति स्वतः न ते हैं तथा स्वतःत्र रहते है और उनके अधिकार समान होते हैं। सामान्य ाता पर ही सामाजिक भेद (social distinctions) आधारित हो सकत हैं।" प्रत्येक राजनीतिक संगठन का लह्य व्यक्ति के प्राकृतिक (imprescriptible) अधि-कारों की रक्षा करना है। ये अधिकार हैं स्वत प्रता, सम्पत्ति, सुरक्षा तथा दमा एव अयाय के विरुद्ध अधिकार । उपरोक्त सभी कथन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त के अनुरूप है। इसके विपरीत, रूसो के विचारों का पूट फ्रेंच अधिकार सम्बाधी निम्न अनुष्येदो में स्पष्ट है

"सम्प्रमुता राष्ट्र व निवास करती है।" (अनुच्छेद 3)

"विधि सामा य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी व्यक्तियों को स्वय या अपने प्रतिनिधि द्वारा उसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। विधि सभी के लिए एक समान होनी चाहिए। सभी नागरिक विधि की इंटिट में समान हैं। अत सभी नागरिक ममस्त सम्मान तथा सावजनिक पद समान रूप से अपनी बोग्यनानुसार प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस सम्बाध म याग्यता एव प्रतिमा के अतिरिक्त उनम किसी प्रकार का कोइ भेदमान नहीं किया जायेगा ।' (अनुक्खेद 6)

अनुच्छेद 4 के अनुसार स्थत त्रता हर उस काम का करने म निहित है जिससे दूसरा को कोइ हानि न हो। इस हप्टि म मौलिक अधिकारा के प्रयोग की इसके अनि रिक्त और नोई सीमा नहीं है कि समाज के अन्य सदस्या को भी समान अधिकारों के प्रयोग का लवसर प्राप्त होना चाहिए। इस सीमा का निर्धारण विधि द्वारा होना चाहिए । अनुच्छेद 6 प्रतिनिधि शासन की व्यवस्था करना है। अय अनुच्छेदी के द्वारा व्यक्ति को मनमाने दण ने बादी बनान, काराबास तथा दण्ड देने का निषेध किया गया है, प्रत्येक व्यक्ति का धार्मिक विचारा सहित स्वत त्रतापूर्वक मायण, लखन एव प्रकाशन की स्वत नता प्रदान की गयी है। सम्पत्ति को पवित्र एवं अनुस्लयनीय अधिकार मीपित किया गया है और सामा य सहमति से करारोपण का विधान किया गया है।

उपराक्त अधिकारा का फ्रांस के कालि-काल म प्रणरूपेण उल्लंघन किया गया था । लेकिन 1789 ई क स्वत त्रना, समानता, लोक प्रमुख, योग्यतानुसार पद प्राप्त करना, विधि के अधीन शासन कान्स के परम्परायत गणत त्रीय सिद्धा ना के के दीम तत्व वन रहे। इन विचारो का महत्व चतुम गणत त्रीय सविधान (1946 ई) की

निम्न प्रस्तावना से स्पप्ट है ⁸

"प्रत्येक मनुष्य जाति, धम, विश्वास क भेदमाव के बिना जनुल्लधनीय एव पवित्र अधिकारों का उपयोग करता है ।" 1789 ई के घोषणा-पत्र म उल्लिति स्वत प्रतामा एव अधिकारी का प्रस्तावना म पुन अनुसमयन किया गया है तथा उ है गणत त्रीय विधि के मुलाघार के रूप म स्वीकार किया है। सविधान मे निम्न राज नीतिक, नामाजिक एव आधिक सिद्धा ता की अत्यधिक महत्वपूण घापित किया गया है।

⁸ Carter, Ranney and Herz . The Government of France, 1954, p. 62.

समी क्षेत्रा म स्त्री एन पुरुषा को निषि के द्वारा समान अधिकारों नी प्रत्याभृति दी गयी है। अत्याचार सं पीडित प्रत्येक व्यक्ति को फेच नवाराज्य में घरण का अधिकार प्राप्त है। अत्येक नागरिक को काम एव रोजगार का निर्माण तथा अधिकार प्राप्त है। इच्छापुसार अधिकार प्राप्त है। एसी सभी सम्मत्त जो राष्ट्रीय सामाजिक सेवा के योग्य
होगी, समाज को सम्पत्ति होगी। व्यक्ति एव पिचार के निकास के लिए आदश्यक
परिस्यित्यों का सरक्षण राष्ट्र का दायित्व है। प्रत्येक व्यक्ति, निर्मयक्तर वृद्ध, श्रमिक
एव स्त्रिया को सम्माजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, निश्वाम एव अवकाश तथा समान धम
निरपेक्ष दिक्षा, एव ब्यावसायिक प्रविक्षण तथा सस्कृति को प्रत्याभृति दी गयी है।
अत्यर्राष्ट्रीय पिषि के पालन, जानाफ युद्ध और स्वत न जनता के विच्छ युद्ध न
छेडने का नवन दिया गया है और समानता एव पारस्यरिकत के आधार पर सम्भृता
की सीमाओ को मायता दी गयी है। का क की सीमा के अत्यत्त समुद्र पार के
चपनिवेश सी सामिल किये गये हैं एव सहा के निवासियों को निवा किसी भेदनाव के
सिवान प्रवत्त सभी अधिकार समान रूप मंत्रान किये गये हैं।

का स के पाँचने गणत नीय सिवधान (1958 ई) की प्रस्तावना में भी यह कहा गया है कि "फेच जनता मानव अधिकारों के प्रति 1789 ई के घोषणा पत्र म परिमापित एवं 1946 ई ने सिवधान की प्रस्तावना द्वारा अनुसमिति एवं पूण रूप में अपने को वचनवढ़ होने की घोषणा करती है।"

1958 ई के पदम गणतान के अन्तगत भी वे समस्त अधिकार फ़ेच जनता की प्रदान किय गये है जो चतुष गणतान ने अधीन उसे प्राप्त थे। इसके अतिरिक्त चतुष मेच गणतान के अनुरुद्धेद 2 ने अन्तग्रत फ़ान्स को धम निरपेक्ष लोकत नीय राज्य पीपित किया गया था। यह अवस्थाएँ महत्वपूण है। इसके अतिरिक्त गणतान का लक्ष्य स्वतानता, समानता एवं आतृत्व था। पौचने गणतान की प्रस्तावना म मह उल्लेख है।

लिकिन फ्रेंच अधिकारो की तुलना अमेरिकी अधिकार-पन से नहीं की जा सकती। फ्रेंच अधिकारो की घोषणा अमेरिकी स्वतं नता को घोषणा के अधिक निकट है। पूमन के अनुसार, यह विधिक प्रपन नहीं है अधितु विद्यानों का एक महान घोषणा पत्र है। कादर का मत है कि 1789 ई के घोषणा-पन के निर्माताओं की मुख्य समस्या राजनीतिक न होकर आधिक अधिकार सम्बन्धी यी। अमेरिकी एव प्रेच अधिकारों स मुख्य अस्य सो के अमेरिकी एव प्रेच अधिकारों स मुख्य अस्य सो के अमेरिकी एव हो के साम के साम

⁹ Newmann European and Comparative Governments, p 223

¹⁰ Carter and others of cut, p 62

किया जाता है। इमलैण्ड एव अमेरिका की भौति विवादो एव नजीरो पर पूणत आश्रित नही रहा जाता। फांस मं प्रशासकीय यायालय हैं। इनके द्वारा शीझ निर्णय कियं जाते हैं। फांस में नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा अपेक्षाकृत अधिक सरसता एवं कम खब मं कराने मं सफल होता है।

सोवियत रूस मे मौलिक अधिकार 11

सोवियत सविधान में, आम एव जिंक के अनुसार, इतिहास म नात सबसे अधिक असाधारण अधिकार पत्र (Bill of Right) का समावेश है। 13 स्टालिन सिव धान की यह सर्वाधिक महत्वपूण विशेषता है। 1918 ई व 1924 ई के सविधानों में मीलिक अधिकारों का उत्लेख नहीं था। 1935 ई तक रूत संसाम्यवादी व्यवस्था के सुदृढ रूप में स्थापित होने पर ही सविधान का निर्माण किया गया। इस सविधान हारा नागरिकों को निक्क अधिकार प्रवास किया गया।

- (1) काम का अधिकार (Right to Work)—प्रत्येक नागरिक को काम का अधिकार प्राप्त है अर्थात नाम की मात्रा एव गुण तथा रोजयार (Employment) के अनुसार पारिश्रमिक के अधिकार की प्रत्येक नागरिक को प्रतिश्लुति प्रदान की गयी है। (अनुच्छेद 118)
- (2) विभाग व अवकाश का अधिकार (Right to Rest and Leisure)— इसके अनुसार काम के घण्टे निश्चित कर विये गये है, श्रमिकों को सवेदन वार्षिक अवकाश प्रदान किया गया है, विभिन्न स्थानों पर अवकाश प्रव विश्वास हेतु आवास गह एवं बलवा का निर्माण किया गया है। (अनुच्छेद 119)
- (3) सामाजिक सुरक्षा का अधिकार—इसके अ तयत वदावस्था, रुग्णावस्या एव अशक्त होने पर राज्य द्वारा प्ररण-पोषण तथा व्यापक सामाजिक सुरक्षा, सामा जिक दीमा, नि शस्क चिकित्सा एवं पेशन की व्यवस्था की ययी है। (अनुक्छेद 120)
- (4) प्रत्येक स्त्री पुरुष को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। सोवियत रूस में शिक्षा पूणत नि शुल्क है। प्रत्येक स्त्री वालक को आठ वप को आयु तक शिक्षा प्रारम्भ कर देना अनिवाय है। शिक्षा का माध्यम स्थानीय सापा होती है। धान्न वित्तयों को समन्तित व्यवस्था है। (अनुष्केद 121)
- (5) हिन्नों एव पुरुषो को समान अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 122 के अत्त यत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र—राजनीतिक,सामाजिक,आर्थिक एवधासकीय—केअतग्र

Refer to chapter X Fundamental Rights and Duties of Citizens of the Soviet Constitution cited by Carter, Renney and Herz Government of the Soviet Union pp. 229-30

^{12 &#}x27;The Soviet Constitution carries one of the most extraordinary Bill of Rights known to the history' — Ogg and Zink Modern Foreign Government, 1951, p 853

समी हित्रयो एव पुरुषो को समान अधिकार प्रदान किय गयं है । इसके अतिरिक्त प्रसूति-ग्रहा एव वालको के लिए शिज्जु विद्यालया की व्यापक व्यवस्था है । अधिक वच्चो वाली माताओ एव अविवाहित महिलाओ के अधिकारो की विशेष रूप से रक्षा की जाती है।

(6) जातीय एव राष्ट्रीय समानता का अधिकार—रूस के अ तगत निवास करने वाली सभी जातिया एव राष्ट्रजातियों को समानता प्राप्त है। वे अपने सास्कृतिक— मापा एव अप रीति-रिवाजा—तथा अप सावजनिक मामलों में पूण स्वतंत्र होते हैं। (अनुच्छेव 123)

(7) धम एव अ त करण की स्थत त्रता—प्रत्येक नागरिक को धम की उप सना एव धम विरोधी प्रचार की पूण स्वतः तता प्राप्त है। राज्य एव शिक्षा के क्षेत्रों को धम से स्वतः त रखा गया है। (अनुच्छेव 124)

(8) सोवियत नागरिको को भाषण एव अभिव्यक्ति (अनुच्छेद 125), समु-दाय निर्माण (अनुच्छेद 126) एव व्यक्तिगत जीवन एव जावास गही की स्वतानता (अनुच्छेद 127) सम्बाधी अधिकार भी प्राप्त है। मापण एव अभिव्यक्ति के अधिकार के अधीन एकतित होने, जलूस निकालने तथा प्रदशन करने की स्वतानता प्रदान की गयी है। इन सभी स्वतानताओं का उपयोग समाजवादी व्यवस्था की इंढ करने के लिए ही किया जा सकता है। समाजवाद का विरोध इन अधिकारो के आधार पर सम्मव नहीं है। समुदाया के निर्माण के अधिकार के अत्तगत प्रत्येक व्यक्ति को श्रमिक-सगठन, सहकारी सस्याएँ एव समितिया बनाने की स्वत त्रता है। परातु इस अधिकार का प्रयोग श्रमिक वग के हिता के अनुकूल और समाजवादी व्यवस्था की सुद्दुढ करने के लिए ही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सोवियत रूस म एकमान दल साम्य-वादी दल है। यही दल राजनीतिक सगठन का जाघार है। साम्यवादी दल' सवहारा वग की कार्तिका अग्रदूत है। अनुच्छेद 127 के अनुसार किसी भी व्यक्ति की पाया लय के निणय एव प्रोक्युरेटर की स्वीकृति के विना ब दी नहीं बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 128 क अनुसार नागरिका के घरा तथा उनके पत्र व्यवहार की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। विधि द्वारा इनकी रक्षा का विधान है। लेकिन ध्यवहार में इन स्वत नताओं का उपयोग साम्यवादी विचारों एवं सोवियत शासन के अनुकूल ही किया जा सकता है।

(9) निजी सम्पत्ति का अधिकार—सोवियत सवियान नागरिका को अपने परिव्यम से अंजित सम्पत्ति को रखते एव उत्तराधिकार म देने का अधिकार प्रधान करता है। अनुरुद्धर 10 के अनुसार नागरिका को अपने काय से हुई आय एव वचत, रहने का मकान, परेलू और निजी सुविधा एव प्रयोग की वस्तुएँ तथा सहायक खेती को अपनी निजी सम्पत्ति के रूप प रखन का अधिकार है। इस उत्तराधिकार

दिया जा सकता है। विधि द्वारा इन अधिकारा की रक्षा की व्यवस्था की गयी है। सोवियत रूस में निजी सम्पत्ति का प्रयोग किसी का शोपण करने के लिए नहीं किया जा सनता। निजी सम्पत्ति के अतगत केवल सुविधा एवं आराम की वस्तुएँ ही आती हैं।

(10) मताधिकार—सोवियत सप मे प्रचाति, राष्ट्रीयता, सम्पत्ति, विक्षा, लिन, पम एव निवास-स्थान आदि के किसी भेदभाव के बिना प्रत्येक 18 वर्षीय सोवियत नागरिक को मताधिकार प्रान्त है। 23 वप की अवस्था पर प्रत्येक रूसी नागरिक को सर्वोच्च सोवियत की सहायता के लिए निर्वाचित होने का अधिकार प्राप्त है।

(11) शरण प्राप्त करने का अधिकार—सिवधान के अनुचड़ेद 129 के अत गत विदेशी नागरिकों को जि हुं राष्ट्रीय स्वात न्य-सचय या वैज्ञानिक कारों म नाग लेने या असिक बग के हिंतों की रक्षा के कारण कोई कष्ट या दण्ड दिया जाता है तो ऐसे विदेशियों को सीवियत क्स में घरण (Asylum) केने का अधिकार है।

सविधान में सोवियत नागरिका के लिए उपरोक्त अधिकारों के साथ-साथ

कुछ मतस्य भी निर्धारित किये गये ह

श्रम सम्मान की वस्तु है अंत काम करना प्रत्येक नागरिक का कतव्य है, जो काम नहीं करेगा उसे रोटो भी प्राप्त नहीं होगी (अनुच्छेद 12)। सोवियत सविधान एवं विधि (अनुच्छेद 130), श्रमिक अनुसासन एवं सावजित्तक कतव्यों का पालन तथा समाजवादी समाज के निवधा का सम्मान (अनुच्छेद 130), सावजितक सम्मित की सुरक्षा (अनुच्छेद्व 131), सैनिक सेवा (अनुच्छेद 132) तथा देश की रसा करना (अनुच्छेद 133) प्रत्येक नागरिक का क्त य है।

मुत्याकत — रूप के सविधान ये उत्तिलखित मीतिक अधिकार जहा परिधम के लोकत त्रीय देशा के मीतिक अधिकारों से मिलते हैं, वहा उनम कुछ नवीनता मी हैं। सोवियत मीतिक अधिकारों को धारणा परिषमी लोकतानिक व्यवस्था की देन हैं पर तु सोवियत मीतिक अधिकारों का छोत सायवारी व्यवस्था है — न कि जान तक द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अधिकारों का छोत सायवारी व्यवस्था है — न कि जान तक दृश्य व्यक्ति को राज्य के विवद्ध शास्वत अनुस्त्यपनीय अधिकार प्रदान करना नहीं हैं अपितु उनका उद्देश्य व्यवस्था को सुद्ध करना है। वे इस निमित्त साधनमात्र है। परिचमी लोकतानिक देशा के मीतिक अधिकारा की प्रकृति नकार स्मक है, लेकिन साम्यवादी रूप ने टाउस्टर के शब्दों म सकारास्पक स्वत प्रताओं (Positive freedom) का प्रतिपाद करने परिचमी लोकतानिक दशा का सारविक्या है। सीवियत रूप स स्वत नताओं से सामाच्या नहीं किया या है। अधित स्वत स्वत प्रताओं की समाच्या नहीं किया या है अपितु यहुँत सं अधिकारा कि प्रता न समरवत्व नताओं सामाच्या नहीं किया या है अपितु वहुँत सं अधिकारा कि प्रता नय स्वत नताओं को समाच्या नहीं किया या है विस्तु वहुँत सं अधिकारा कि प्रता नय स्वत नताओं को समाच्या नहीं किया या है विस्तु वहुँत सं अधिकारा कि प्रता नय स्वत नताओं के समाच्या है। स्वत नाता कर स्वत नताओं के समाच्या नहीं किया व्यवस्था स्वत नताओं समाच्या है। स्वत्य स्वत स्वताओं स्वता नया है। स्वत्य स्वत स्वताओं स्वता स्वत्य स्वत स्वताओं स्वता स्वता

¹³ In the Bill of Rights of the new Constitution, the Soviet Union has followed the Western democracies with regard to the nega

के अन्तरात वृद्धावस्या में सहायता, विश्वाम व अवकाश एव विश्वा सन्व यी अधिकार है। मारतवय म इस प्रकार का प्रावचान मोलिक विधिकारा की अधेका तीति तिवेशक तत्वों के अन्तरात किया गया है। सोवियत रूस म नागरिक एव राजनीतिक अधिकारों को अपेका आर्थिक अधिकारों के अनियत्वित के सोवियत रूस म स्थीकार नहीं किया गया है। परिचमी लोकतानिक देशों म उत्पादन के साधनों पर निजी सम्पत्ति को व्यवस्था है। अत निजी सम्पत्ति रोपण तथा उत्पीदन का साधन वन गयी है। इसके विपरीत सोवियत रूस म सम्पत्ति एव उत्पादन के साधना पर सामाजिक स्वामित्व है। निजी सम्पत्ति में जीवनोरयोगी सुविधा की वस्तुआ को हो शामिल किया जाता है। परिचमी लोकत नो म व्यक्तिया के अधिकारों की धूम हैं परन्तु कत्तव्य की कही कोई चर्च नहीं है। सोवियत रूस एवं चीन जसे समाजवादी देशों में अधिकारों के साथ कतव्यों का भी उत्लेख विया गया है।

सोवियत मौलिक अधिकारा की साम्यवादी विचारको द्वारा प्रशसा की गयी है। स्टालिन ने इन व्यवस्थाओं पर गव व्यक्त किया था। साम्यवादी विचारक लोकत जीय अधिकारो को कानजी घोषणाएँ मान मानते हैं। स्वत त्रता तथा समानता की घोषणा मान से उन्ह प्राप्त नहीं किया जा सकता है। स्वतानता एव समानता की ऐसी 'सामाजिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है जिनमे व्यक्तित्व समग्र रूप से विकसित हो सके। ध्यक्तित्व के विकास का आधार ही आधिक स्वत नता है। रूस न इस आधिक अभाव एव शोपण से व्यक्ति की रक्षा की गयी है। कारिप सकी का क्थन है कि "सावियत भौतिक अधिकार एव स्वत नताएँ न तो पूजीवादी देशों में हु ही और न वे उनम हो ही सकती हैं।"36 फाइनर, मुनरो, पुमन जसे पश्चिमी विचारक सोवियत अधिकारी को दिखावा मान मानते है क्योंकि सोवियत शासन सवाधिकारवादी है। वहाँ साम्यवादी दल का अधिनायकरव है। सीवियत रूस मे व्यक्ति की अपेक्षा सवहारा वग-श्रमिका एव कृपको-के हितो को प्रधानता दी गयी है। उपरोक्त अधिकारा म से कुछ के परीक्षण से इस मत की बहुत कुछ पुष्टि हो जाती है। सोवियत राज्य मे शिक्षा पर राज्य का निय त्रण है और उसका आधार साम्यवादी दशन एव विचार हैं। अत उदार शिक्षा के लिए रूस म कोई अवसर नही है। साम्यवादी दशन की दीक्षा दना ही शिक्षा का प्रवान उद्देश्य है। सोवियत रूस में विचार, भाषण एवं अभि यक्ति की स्वतातता. विशि सकी के अनुसार, समाजवाद के धनआ को उपलब्ध नहीं है और श्रमिका के इन अधिकारो को हानि पहुँचान के प्रत्येक काय को 'ऋति विरोधी काय' माना जाता

tive freedom while it has pioneered in the introduction of positive Freedom "—Towster $\begin{tabular}{ll} Polytical Power in the USSR, pp 380 81 \end{tabular}$

¹⁴ V Karpinsky The Law of the Soviet State, pp 219 20

है। सावियत रूस म बुर्जुआ, मैनघोविष्टा (Menshevists) एव ऋति विरोधियो के समाचार पत्रों को समाप्त कर दिया गया है तथा समाजवाद विरोधी साहित्य एव साहित्यकारों को वहा कोई स्थान नहीं है। डॉ जिवागों के लेखक का पस्टरनायक को रूस म कोई स्थान नहीं था। स्टालिन की पुत्री स्वेतलाना को भी साम्यवादी शासको से मतभेद होने की अवस्था म सोवियत रूस छोडना पडा था। धार्मिक आचरण सम्ब धी स्वत बता के सम्बाध में यह कहना अधिक ठीक है कि प्रत्येक नागरिक को धम विरोधी स्वत नता अपेक्षाकृत अधिक प्राप्त है। व्यक्तिगत जीवन एव गही की स्वतानता का अधिकार व्यवहार म साम्यवादी दल के सदस्या एवं उनके समयको को ही प्राप्त है । सीवियत एस म मौलिक अधिकारो की रक्षा का दायित्व मारतवय एव सयक्त राज्य अमेरिका तथा अय देशों की मौति सर्वोच्च यायालय पर नहीं है। स्मरणीय है कि पारचात्य सविधान शास्त्रियो की हप्टि मं याधिक सरक्षण के अभाव मं मौलिक अधि-कारों का कोई महत्व नहीं है। रूसी जनता को मत देने का अधिकार तो है परन्तु वे उसका स्वत जतापवक उपमोग नहीं कर पाते हैं । क्यांकि देश म एकमाज साम्यवादी दल है, उसी के द्वारा प्राय उम्मीदवार खड़े किये जाते हैं एव वे ही निर्वाचनों में विजयी होते हैं। अत सोवियत नागरिकों के समक्ष कोई बैकल्पिक शासन नहीं है। साम्यवादी दश्न म राजनीतिक स्वत त्रता की अपेक्षा आर्थिक स्वत त्रता को वैयक्तिक एव सामा-जिक उन्नति के लिए आवश्यक माना जाता है। सोवियत रूस म व्यवहार मे मौलिक अधिकार, वास्तव म शासन द्वारा निश्चित किये जाते हैं। सीवियत रूस एव पश्चिमी प्रजात ना में स्वत नता सम्बन्धी मुख्य भेद यह है कि सीवियत रूस में स्वत नताओ का पुणरूपेण दमन करने के परचात उनके अनक भिन्न अम किये गये है एवं उन पर निरन्तर बल दिया जाता है।¹⁵

उपरोक्त विश्लेषण स यह निविवाद रूप म स्पष्ट हो जाता है किसो विश्वत रूस मे आर्थिक अधिकारो की प्रधानता है। वयक्तिक स्वत त्रता या नागरिक स्वत त्रता को बहा अपेशाकृत कम मान्यता प्राप्त है। मनुष्य हाड मीस का पिण्ड मात्र नहीं है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए विचार एव अमिव्यक्ति की स्वतात्रता तथा वकिएक सासन निर्माण सम्ब वी अधिकार एव अवसर अनिवाय हाते है। रूस म एक बडी सीमा तक इनना अभाव है।

जनवादी चीन में मौलिक अधिकार

साम्यवादी चीन के सर्विधान द्वारा नागरिको को निम्नलिखित अधिकार एवं कत-य^{ाव} प्रदान किय गर्ने हैं

(1) विधि के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। प्रत्येक वयस्क नागरिक—

¹⁵ Towster op at p 380

¹⁶ अध्याय 3---अनुच्छेद 85, 99

हिनयों एव पुहुषों—को 18 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने पर बिना किसी भेद भाव के मतदान एव निर्वाचन में माय लेने के अधिकार प्राप्त हैं। वेकिन साम तो एव वुर्जुंगा पूजीपित्वा को मताधिकार से विचित कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को जन-पायालय के निजय या जन प्रोक्यूरेटर की अनुमति से ही ब दी बनाया जा सकता है। वीनी नागरिकों के निवासगृहों के क्षेत्र का उल्लंबन नहीं किया जा सकता है। उहे आवास एव उसके परिवतन करने की स्वत त्रता प्राप्त होती है (अनुच्छेद 90)। पत-क्ववहार सम्ब धी मोपनीयता विचि हारा सरक्षित है। ये व्यवस्थाएँ सोवियत सविधान के समान है। है। भी भाषा भी बोनों को समान है।

- (2) काम एक विकास का अधिकार—अमिको एव अ'य कमचारिया के काम एव छुट्टी के घण्टे निश्चित हैं। अमिको को अ'य भौतिक सुविधाए भी प्राप्त हैं जिससे विधास करके वे स्वस्थ रह सकेंगे।
- (3) प्रत्येक नागरिक को वृद्धावस्था, रूग्णावस्था एव असमयता की दद्या में मीतिक सहायता (Material) का अधिकार प्राप्त है। इस हेतु राज्य द्वारा सामाजिक वीमा, सामाजिक सहायता एव सामाजिक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था की गयी है।

(4) शिक्षा का अधिकार—शिक्षा हुतु सारे देश मे विभिन्न प्रकार के विद्या लयो, सास्कृतिक एव शक्षणिक सस्याओं को स्थापना की गयी है। वज्ञानिक शोध, साहित्यक, कलात्मक एव सास्कृतिक कार्यों को राज्य द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है तथा युवकों के शारीरिक एव मानसिक विकास का राज्य विशेष ज्यान रखता है।

- (5) धार्मिक विश्वास की स्थत जता—नागरिका को धार्मिक रूप से स्वत जता प्राप्त है। उपासना एव अत करण की स्वत जता की हप्टि स धार्मिक सस्थान। से राज्य एव शिक्षा को पृथक कर दिया है। धम के विश्वे प्रचार की स्वत जता सभी नागरिकों की प्राप्त है।
- (6) हिन्समें को समानता का स्तर प्रदान किया गया है। जनवादी बीन म जीवन के सभी राजनीतिक, आधिक, सास्कृतिक, सामाजिक एव पारिवारिक क्षेत्रा म हिन्दा नी पुरुषा के समकक्ष स्थान प्राप्त है। राज्य द्वारा विवाह, परिवार, माताआ एवं वालका को सरक्षण दिया जाता है।
- (7) फट्ट निवारण का अधिकार प्रत्येक चीनी नागरिक की प्राप्त है। यदि किसी शासकीय विभाग या कार्यालय या अधिकारी द्वारा किसी विधि का उल्लधन किया जाता है अथवा कलव्य का सम्मादन नहीं किया जाता तो नागरिका को लिखित एवं मौखिक रिकायत करने तथा हानि की शांतिपृत्ति करने का अधिकार है।

प्रवासी चीनिया के उचित हितो एव अधिकारो की रक्षा का दायित्व जनवादी चीन के जनवादी मणराज्य पर है। उचित काय के लिए दण्डित विदेशिया या जनआन्दा

¹⁷ देखिए सोवियत सविधान के अनुच्छेद 127 एव 128

लनो अथवा वैज्ञानिक कार्यों में सलम्म व्यक्तियों को चीन में घरण प्राप्त करने का अधि कार है। सभी नागरिका को भाषण, प्रेस, सभा आयोजन तथा सथ, जलूस एव प्रदयन करने की स्वतानता प्राप्त है। राज्य के द्वारा इन स्वतानताओं के उपभोग की प्रत्या भूति आवस्यक मीतिक सुविधाएँ प्रदान करके दी गयी है। भाषण एव प्रेस की स्वतानताओं का उपभोग श्रमिकों के हितों के अनुरूप ही किया जा सकता है। बीन के जनवादी लोकताभ का लक्ष्य पूजीवाद को समाप्त कर माजजबाद की स्वाप्त करना है। श्री के उपभोग क्रिक के स्वाप्त कर माजजबाद की स्थापना करना है। श्री उपपोक्त स्वतान्य तथा है विरोधियां की कोई स्थापना एवं प्रसार के सल्क्ष में ही प्राप्त हैं। समाजबाद के विरोधियां की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हैं। उन्हें देखदोही एवं क्षांति विरोधी होने की सना दी जाती है।

भौतिक कतथ्य¹⁸—सोवियत सविधान की भौति चीन के सविधान म मी नागरिकों के निम्न कतथ्यों का उल्लेख है

नागरिका को सविधान एव विधि के अनुरूप कार्य करना चाहिए। अनुशासन को कायम रखना, साजनिक व्यवस्था एव सामाजिक आचार की रसा, जन-गणराज्य की सम्पत्ति की सुरक्षा अर्थक चीनी नागरिक का कतव्य है। प्रत्येक नागरिक को विधिसम्मत कर अदा करना चाहिए। सनिक संवा एव देश की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का पवित्र कतव्य है।

चीन के जनवादी सविधान से मौलिक अधिकारो एवं कतव्या सम्बाधी एक प्रथक अध्याय है। इसमें मताधिकार सहित अय नागरिक अधिकारी की प्रथम एव आर्थिक अधिकारो को दिलीय स्थान प्रदान किया गया है। चीन म भी सोवियत रूस की माति नागरिक अधिकारो (Civil rights) की व्यवस्था सहस्र समाजवादी व्यवस्था के निर्माण एव अनुरक्षण की हृष्टि से की गयी है यदापि चीन के सविधान में सीवियत सविधान की मांति इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख नहीं है । सोवियत रूस की मांति चीन मे भी साम्यवादी दल ही एकमान राजनीतिक दल है। शासन लोकतानिक के द्रीकरण पर आधारित है। लोकतान पर कम और के द्रीकरण पर अधिक बल दिया गया है। देश की समाजवादी व्यवस्था के विरुद्ध काय आति विरोधी पड़य प माना जाता है। लोकता निक देशों की माति भाषण एवं विचार अभिव्यक्ति तथा समा, सघ बनाने की स्वत त्रताएँ चीन जनता का प्राप्त नही हैं । यह स्वत त्रताएँ तमी तक माय है जब तक कि उनका साम्यवादी विचारधारा से कोई विरोध नहीं है। ऋति विरोधी कार्यों को देशद्रोहात्मक काय माना जाता है और सर्विधान में उसके दमन का आदेश है (अनुच्छेद 19) । मौलिक अधिकारो का चीन म कोई व्याव हारिक महत्व नहीं है। कतव्य के पालन के जमाव मे मौलिक अधिकारो का कोई अस्तित्व नहीं है। अकारण ही लाखो लोगो की चीन म हत्या की गयी है। विधि

¹⁸ अनुष्छेद 100 103

व पाम का बीन में कोई बस्तात्व है। साम्मवादी दन का ज्यून पान क्यान संगठन एवं कापपद्धित पर एकांपिकार है। बीन में क्यून ब क्यान क्यान कर रहें पर है। के दक्कत नियोजन, कम्यून प्रणाती एवं क्यार दर्वे के स्वतन कर क्यान क्यान के देकिए को क्यान में कि क्यान के क्यान के क्यान का क्यान क्यान

पूर्वोस्ताविया से नागरिक स्वत उताएँ, विवकार तथा कार्यां पूर्वोस्ताविया से विविधान में व्यक्तिया है । नाग्यें के जिल्लामं के सी क्षाप प्राप्त करायों का प्रीराचिता, वार्ति, वच्ने हैं । नाग्यें के के क्षाप प्राप्त करायों का प्रोप्तिवा, वार्ति, वच्ने के लाग्यें के प्राप्त के विना समानता प्रदान को तथा है क्षाप्त के किया के विना समानता प्रदान को तथा है क्षाप्त के किया के का सामाजिक स्वधावन का व्यक्तिय का क्षाप्त के का सामाजिक स्वधावन का व्यक्तिय क्षाप्त के का सामाजिक स्वधावन का व्यक्तिय क्षाप्त है । का व्यक्तिय का व्यक्तिय का वार्तिय का वार्तिय का सामाजिक स्वधावन का व्यक्तिय क्षाप्त के का वार्तिय का वा विश्वास पर कोई प्रतिव घ नहीं है। हर कोई अपने घम का प्रचार कर सकता है। राज्य चच के निय चण से स्वत व है (अनुच्छेब 47)। किसी व्यक्ति के जीवन एवं निया जा सकता है। किसी व्यक्ति के जीवन एवं में किसी व्यक्ति के जीवन एवं में विभि के अनुसार ही किसी व्यक्ति को नजर वर किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को में किसी काम के निए विष्ठत नहीं किया जा सकता है जो किये जाने के समय अपना नाता हो (अनुच्छेब 48 एवं 49)। प्रत्यक व्यक्ति को नाम संस्था वसने की स्वत प्रात्त है। नामिश्च के स्वत प्रवास के स्वत प्रवास के अपना प्रवास है। नामिश्च को क्षेत्र माना ना सकता है। पर वुं शासन को स्वास्थ्य एवं देश को पुरक्षा को ही पर अतिक एक किसी मान से अतिक एक नामिश्च के समय अतिक मान को स्वास्थ्य एवं देश को पुरक्षा को ही जा सकती है। इसी प्रकार पत्रों पत्र विवास वारण्ड किसी माना की ताला है। विश्व जा सकती है। इसी प्रकार पत्रों एवं पत्र व्यक्ति की भीपनीयता का अतिक का विश्व जो एवं व व व्यवहार की भोपनीयता का अतिक का विश्व जो उसता है वुं इसे सीमित या निचिन्छत किया जा सकता है। उसी प्रकार पत्रों एवं पत्र व्यवहार की भोपनीयता का अतिक का विष्ठ को स्वास है अनुच्छेब 52)।

प्रत्येक नागरिक की रक्षा के लिए प्रणराज्य कतव्यवद्ध है। किसी नागरिक की नागरिका के अधिकार से बन्तिन नहीं किया जा सकता और न उस प्रत्यावधित हीं किया जा सकता और न उस प्रत्यावधित माताओं एवं वच्चों को निवोध स्रत्याण प्रदान किया गया है। वरिवार की गयी है। प्रत्यार की नायी है। वरिवार को मायता मातत्व तथा पारिवारिक सम्बन्धों को विधि होरा नियमित किया गया है। विवाह एवं (अनुच्छेद 58)।

कतन्य-देश की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का अधिकार एव सर्वोच्च कतव्य है। सावजानक पदा का पूण निष्ठा ते सत्यादन, सविधान एव विधि का पालन, समाज की मीतिक समित्र में सामर्थानुसार योगदान मत्येक नागरिक का कतव्य है। सविधान हारा प्रवत्त स्वत-नताओं एव अधिकारों की मतमाने दण से कम या सीनित करना सद्यानिक एव रण्डनीय अपराध माना गया है और इनके सरकाण के लिए यायिक सुरक्षा की व्यवस्था है। अधिकारा के सरकाण का बायित्व यायालय का है।

सीवयत रूस एव बीन के सविधाना हारा प्रदत्त अधिकारों की तुनना प प्रगोस्लाविया है मिवधान हारा अधिक स्वत-त्राएँ प्रदात अधिकारों की तुनना प म इनका अतिक्रमण नहीं निया जा सकता है और न विधियों हारा में सीमित ही की का सकती हैं। अधिकारों की रक्षा के लिए याधिक सरसाण भी प्राप्त हैं। पूरोस्लाविया प्रगोस्लाविया म सीविधत रूस एव चीन की भाति एकमात्र दल साम्याची पर तु है। वहाँ पित्र की सांकित न नहीं हैं। अब इन स्वत त्रताला की वास्तविकता में म देर हैं। सीविधत रूस की भाति पूगोस्लाविया के सविधान म अधिकारों की पूर्ति हेतु आवश्यक स्थिति का उत्सेख नहीं हैं।

34

भारत मे मौलिक ग्रधिकार' [FUNDAMENTAL RIGHTS IN INDIA]

मारतीय सविधान में मौलिक अधिकारो एव नीति निर्देशक तत्वो पर पूपक पूपक—जुतीय एव चतुथ—अध्याय हैं। इस सम्बाध में मारतीय सविधान निर्माता अमेरिकी अधिकार पन, फोच मानव अधिकारों की धोएणा एव आयरिश सविधान (1935 ई) से प्रमावित थे। "सविधान निर्माणकाल के मध्य (1948 ई) म ही समुक्त राष्ट्र सम ने मानवीय अधिकारों सम्बाधी धोपणा पन को स्वीकार किया था। कांग्रेस उदारवादिया, राष्ट्रीय जीवन के समस्त नरमदसीय कोनो एव घामिक अध्य-सहस्वको—मुसलमानो सिक्की, ईसाइयो—ने सविधान में मौलिक अधिकारों के उत्तरेख को अस्पस्यको—मुसलमानो सिक्की, ईसाइयो—ने सविधान में मौलिक अधिकारों के उत्तरेख को अस्पस्यकों के अधिकारों की रक्षा एव बहुसस्यक के विश्वसास हुत वाधनीय माना था।

धान में लिपिवढ करने का निणय लिया था—प्रथम, ब्रिटिशकालीन निरपुराता एव असमानता सम्य भी अनुमव, द्वितीय, जाति प्रया के परिणामस्वरूप अछूतो की दयनीय स्थिति, एव तृतीय, मारत म विभिन्न धार्मिक, भाषाधी एव जातीय (tacial) अल्प-सस्यको का अस्तित्व तथा उनके सास्कृतिक अधिकारा की सुरक्षा की आवश्यकता।

सर्विधान समा के सभी पक्षी ने भी सर्विधान ममीलिक अधिकारों के उल्लेख का स्वागत किया था । सर्विधान-निर्माताओं ने तीन अ"य कारणा से मौलिक अधिकारा को सवि-

सह्यको को शास्त्रत तथा उनक सारकाराक आधकारा का सुरक्षा का आवरयकता। भारतीय सविधान के अतगत प्रत्येक नागरिक को निम्नलिसित मौलिक अधि-कार प्राप्त हैं

(1) समानता का अधिकार (Right to Equality) अनुच्छेद 14 से

¹⁸ तक । 1 मारतीय सर्विमान, अध्याय 3, अनुच्छेद 12 से 32 तक ।

हितीय विश्वयुद्धोत्तरकालीन वर्मी एवं जापानी सविधाना का मी प्रमाव पडा है। स्मरणीय है कि वर्मा एवं भारत की समस्याएँ बहुत कुछ समान थी। जापानी सविधान पर अमेरिका का विशेष प्रमाव था।

³ Pylee, M V India s Constitution, p 79

- (2) स्वत त्रता का विषकार (Right to Freedom)—अनुस्केर 19 ते
- (3) शोपण के विरुद्ध व्यथिकार (Right against Exploitation)—अनु च्छेत्र 23 एवं 24 ।
- (4) धार्मिक स्वत वता का अधिकार (Right to Freedom of Religion)—अनुन्त्र 25 से 28 तक।
 - (5) सास्कृतिक एव सराणिक अधिकार (Cultural and Educational Rights) - अनुच्छेद 29 एवं 30 ।
- (6) सम्पत्ति का अधिकार (The Right to Property)—अनुबहेद 31, 31 (अ) एवं अनुच्छद 31 (व)।
- (7) सबधानिक उपचारों वा अधिकार (The Right to Constitutional Remedies) अनुच्छद 32 । समानता का अधिकार इस अधिकार का अथ है कि—

(1) प्रत्येक नागरिक विधि की हृष्टि म समान है तथा सभी की विधि का समान सरक्षण प्राप्त है। (2) सावजनिक मनोरजन के स्थाना पर जाने एव सावजनिक कुंजी तालावा,

घाटो, तडको के प्रयोग करने तथा राज्य के अतगत किसी पद या नियुक्ति के सम्बन्ध म किसी भी नागरिक क साथ रक्त वण, जाति लिय एव ज मस्यान के आपार पर कोई अयोग्यता दायित्व, प्रति या प्रतिव घ मही लगाया जा सकता। अस्पृत्यता को निपिद्ध करते हुए उसके आधार पर भेवमान को अपराध घोषित किया गया है।

(3) सैनिक एव प्रसणिक उपाधियों को छोडकर राज्य हारा अन्य कोई उपाधि प्रवान नहीं की जा सकती और न कोई मारतीय किसी विदेशी राज्य से कोई जपाधि ही स्वीकार कर सकता है। इसी प्रकार भारत सरकार के लेवारत विदेशी कमचारिया द्वारा विना राष्ट्रपति की अनुमति के विदेशी राज्या द्वारा प्रदत्त उपाधियाँ स्वीकार नहीं की जा सकती है।

अंतुम्छद 1/। वर्णुरवता अपराव वाचानवम् (१४३३ १) आ नमाण् एरा सदद ने इस सर्वेद्यानिक प्रावधान को और अधिक स्पष्ट कर दिया है। इसके संबद न इस संबंधानक प्रांबधान का बार बापक स्पष्ट कर दिया है। इसक अनुसारित जोतियों के लिए भी बुंजी हैं तथा बेनुसीरत वातियों के हैं है वे बेनुसीरत जोतियों के लिए भी बुंजी हैं तथा बेनुसीरत वातियों के हैं है वे कारों में हस्तियें करने बाले काथ को दफलोध बेनुसीरत वातियों के हैं है वे कारों में हस्तियें करने बाले काथ को दफलोध बेनुसीरत वातियों के हैंन बिंच कारों में हस्तियें करने बाले काथ को दफलोध बेनुसीरत वातियों के हिन्न बेन्द्र काथ किये भारत में हराजा मेरा मान का अञ्चलक का अमिना मान है जा कर स्वास मा 500 है तक का अमिना या सेना देख दिये जा सकते हैं। अनुच्छेद 18

समानता का अधिनार असीमित नही है। बुद्ध राज्यो या म्यानीय क्षेत्रा म नौकरी सम्याधी आवासी योग्यता निर्धारित करन एव अनुसुचित जातिया के लिए स्पान सुरक्षित चरन का अधिकार ससद को प्राप्त है। सावजनिक स्थानो म जाने के समान अधिकार ने अत्तवत स्त्रिया एवं बच्चा के लिए विश्वेष व्यवस्था करन का अधि कार राज्य को प्राप्त है और उसे इस अधिकार से बिचत नहीं किया जा सकता।8 इसक अतिरिक्त इस विधवार के कारण धार्मिक सम्धावा की प्रश्च धवारिणी के सदस्यो एव अय पदाधिकारिया पर धम के अनुयायी होने पर काई प्रतिवाध नहीं लगाया जा सकता है। प्रथम सब वानिक सशोधन द्वारा इस अधिकार के सम्बाध म यह ध्यवस्था की गयी है कि समता के अधिकार के फलस्वरूप सामाजिक एवं हीक्षणिक इस्टि से पिछडे वर्गों एव नागरिका या परिगणित जातियो और जनजातिया हेतु विशेष प्रावधान करन के राज्य के अयत्नी पर काई प्रतिवाध नहीं लग जाता है। 10 महास उच्च चायालय द्वारा तक्तीकी विक्षा सस्याओं में विशेष जातिया एवं समुदायों के लिए स्थान सरक्षित करने वाले मद्रास राज्य के शासकीय आदेश की अवैधानिक घोषित कर दिये जाने पर यह सदीधन पारित किया गया था।11 समता के मौलिक अधिकार मे उल्लिखित 'विधि के समक्ष समानता' प्रस्तावली को डायसी द्वारा अस्तिविक विटिश 'विधि के शासा' के सिद्धा ता से ग्रहण किया गया है। इसना अध निरक्श शासन का अमाव एव विधिक समानता अर्थात प्रशासनीय विधि ना अमान है। प्रत्येक नागरिन चाहे उसकी स्थिति कुछ भी क्यों न हो, एक ही विधि के अधीत है एवं उसी के द्वारा शासित है। 'विधि का समान सरक्षण' (equal protection of law) शब्दावली समरिका के 14वें सबैधानिक संशोधन की उपधारा में से उदधत की गयी है। असे-रिकी सबोच्च "यायालय ने इसकी ब्याख्या करते हुए वहा है कि 'सब व्यक्तियों को सूख एव सम्पत्ति प्राप्त करने तथा उसका उपयोग करने का समान अधिकार है। उन्ह अपने व्यक्तित्व एव सम्पत्ति के सरक्षण क लिए 'यायाल्या एव अ'यायी के प्रतिकार तथा अनुबाधा के जिया वयन हेतु यायालय की शरण लेने के समान अधिकार हाने चाहिए । किसी व्यक्ति के कार्यों पर ऐसे कोई प्रतिवाध नहीं होन चाहिए जो समान परिस्थितियों में कि ही अप व्यक्तियों पर न नगाये जायें तथा समान व्यवसाय एव परिस्थितिया मे अय लोगो पर आरोपित आर्थिक या कर भार से अधिक कर भार आरोपित नहीं किया जाना चाहिए। फौजदारी याय के प्रशासन म किसी व्यक्ति को

अनु**च्छेद 16 (3) (4)** 7

अनुच्छेद 15 (3) 8 अनुच्छेद 16 (5)

प्रयम सशाधन 1951 ई बनुच्छेद 15 (4)

Chambakaran Dorairanjan vs State of Madras, A I R 1951 B 11

948 | जाघुनिक शासनत त्र

समान अपराघ के लिए दूसरे स मिन अथना अपिक दण्ड नहीं दिया जाना

विधि के समक्ष समानता एवं 'विधि का समान सरक्षण' दोना सन्दावित्या का उद्देश स्थिति (Status) एवं अवसर (Opportunity) की समानता स्थापित करना है। 'विधि क समझ समानता वाक्याच नकारात्मक समानता सम्बंधी जास्वा-सन है, जवकि 'विधि का समान सरक्षण' सकारात्मक या स्वीकारात्मक अपौं म समा नता वा आस्वासन है।

अनुच्छेद 14 द्वारा राज्य के भेदमान सम्ब धी कार्यों पर प्रतिव घ लगाया गया है विकिन स्यक्ति के कार्यों पर कोई प्रतिवाध नहीं हैं। व्यक्तिगत फुमों म काय करने बाते कमचारियों के साथ यदि मालिक के डारा कोई भेदमान किया जाता है तो इस मकार के विभेद से रहा। के लिए विसी प्रकार के यायिक सरकाय की कोई व्यवस्था मही है। यदि इस प्रकार ने वैयक्तिक कार्यों सन्वाधी भेदमाव के बार य हस्तक्षेप की कोई व्यवस्था होती तो व्यक्ति की स्वत यता अत्यिषक सीमित हो वाती और मीलिक अधिकार स्वय में ही महत्वहीन ही जाते। यह इसका सकत है कि व्यक्तिगत एव तामाजिक हिता की सीमाएँ होती है। व्यक्तिगत दित वहाँ सामाजिक दित का अति त्रमण करने लगता है वही सिवपान निर्माताओं न राजकीय हस्तक्षेप की व्यवस्था को है जदाहरणाय, अस्ट्रह्यता को सविधान म वण्डनीय अपराध बीपित किया गया है। स्वत नता का अधिकार

स्वत त्रता के अधिकार के अ तगत प्रत्येक मागरिक को निम्मलिखित स्वत व प्रवान की गयी है (व) मापण एव विचार-अभिव्यक्ति की स्वतः नता ।

- (व) विना शस्त्र शातिपुवक सम्मेलन करने की स्वत त्रता । (स) समुदाय या सघ यनाने की स्वत नता।
- (द) मारत के निसी भी भाग में निनास करने एन वस जाने की स्पत प्रता। (इ) सम्पत्ति के भाजत करने, रखने एव विक्रय करने की स्वव नता।
- (ई) कोई वित्ति अथवा व्यापार वाणिव्य या कारोबार करने की स्वत त्रता। उपर्युक्त स्वत त्रताओं के हुस्पयोग को रोकने के लिए संविधान द्वारा साव-मीमिक रूप में इन पर कई प्रकार के प्रतिव च लगाये है

मापण एव विचार अभिव्यक्ति की स्वतः त्रता पर सातः प्रतिब छ हैं । मूल

¹² Quoted in D N Banerjee Our Fundamental Rights Calcutta 13 अनुच्छेन 19 (1)

सविधान में केवल चार प्रतिबाध ही थे। प्रथम संशोधन (1951) के द्वारा तीन अन्य प्रतिबाधा को और जोड दिया गया है। य प्रतिबाध है राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्या के साथ मैत्रीपूण सम्ब ध, सावजनिक व्यवस्था, शिष्टता एवं सदाचार या नैतिकता, "यायालय का अपमान करना या उसे वदनाम करने के प्रयत्न एव हिसात्मक कियाओं को उमारना । विसी व्यक्ति के मापण एव विचार अमिव्यक्ति पर उपर्युक्त स्थितिया मे राज्य को उचित प्रतिवाध लगाने का अधिकार प्राप्त है। 14 स्मरणीय है रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य विवाद¹⁸ म सर्वोच्च "यायालय ने यह निष्मय दिया है कि जब तक मापण एवं विचार-अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लक्ष्य राज्य की सुरक्षा की समाप्त करना और राज्य को उखाड फेकना नही है, तब तक प्रतिवन्य निर्धारित करने वाली विधि को उचित प्रतिव ध नहीं माना जा सकता। इस व्याख्या के अनुरूप सर्वोच्च 'यामालय एव कुछ उच्च 'यायालया ने अपने निणया म यह मत व्यक्त किया है कि अनुच्छेद 19 (2) द्वारा निर्धारित सीमाओं के बातगत व्यक्तिगत हत्याओं एव असन्तोप को बढावा दर्न वाले कार्यों को सीमित नहीं किया जा सकता। इस कठिनाई को दूर करन के लिए प्रथम सबैधानिक संशोधन के माध्यम से सावजनिक व्यवस्था एव हस्तक्षेप के अप आधारों को अनुक्छेद 19 (2) मे और जोड दिया गया है। इस सङ्घाधन से शासन को हस्तक्षेप क अधिक अवसर प्राप्त हो गये है परात फिर भी प्रतिबाध के औजित्म सम्बाधी परीक्षण का अवसर यायपालिका को ही प्राप्त है।

विचारा नौ अभिन्यांकि के अत्तगत ही प्रेस की स्वत तता प्राप्त है। कोई पृषक प्रत्याभूति इस सम्बन्ध म सविधान डारा प्रदान नहीं की गयी है। इसनी तीव आलोचना की गयी है। इस सम्बन्ध में डा अम्बवकर का यह मत या कि प्रेस काई पृथक व्यक्ति नहीं है। सम्पादक एवं प्रेस के मैंनेचर सभी नागरिक होते है। अत पृथक कप में प्रेस की स्वत त्रता की आवश्यकता नहीं है और अभिन्यक्ति की स्वत त्रता में ही प्रेस की स्वत त्रता भी निहित है।

मिषधान ने अधीन सार्वजनिक व्यवस्था एव नितक्ता के हित म राज्य को सम्मेलन करने एव समुदाय निर्माण की स्वत नता पर उचित प्रतिवाय लगाने का अधिकार प्राप्त है 110 किसी भी नागरिक नो उसकी इच्छा के विवद्ध विसी समुदाय या सगठन का सदस्य नगाने के लिए बाच्य नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च यायासय न महाम राज्य वनाम जी एस राज (1952) नामक विवाद न यह यत व्यक्त किया है कि इस स्वतंत्रता पर उस समय तक प्रतिवाय नहीं समाया जा सकता जब तक कि प्रतिवाय के आसारा जी किसी यायिक अधिकारी के द्वारा समुचित औव न हो

¹⁴ अनुच्छेद 19 (2)

¹⁵ Ramesh Thappar vs State of Madras, A I R 1950 E C 124

¹⁶ वनच्छेद 19 (3) एव (4)

950 | आधुनिक शासनत त्र

जाय । सिवधान के अनुरूप भारत में स्वन त्रतापुरक पूमने, किसी माग में निवास करने एव स्थायी रूप से बस जाने तथा सम्पत्ति अनित करने, रखने एव बेचने पर सामा य जनता अथवा किसी अनुसुचित जनजाति के हितो की रक्षाय राज्य को उचित प्रतिब घ लगानं का अधिकार है। लेकिन जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बाध म राज्य की यह शक्ति सीमिन है। नहीं गैर क्श्मीरियों की भूमि खरीदने का कोई अधिकार नहीं है। व्यवसाय की स्वत नता पर भी सावजनिक दिव में राज्य द्वारा जिंवत प्रतिन ध लगाये जा सकत हैं और कुछ व्यवसायों के सम्बाध म व्यावसायिक एवं तकनीकी योग्यताएँ जी निर्धारित की जा सकती हैं। राज्य का स्वय या राज्य-स्वामित्व या उसके अधील निगम द्वारा नियमित व्यापार उद्योग या सेवा के स्वानित्व को स्वय लेने या सचालन को स्वय ग्रहण करने के अधिकार हैं। ऐसी स्थिति म सम्बचित उद्योगा से राज्य कुछ नागरिको को काशिक या पूणक्ष्पेण पृथक कर सकता है। उद्योग एव व्यवसाय की स्वत नता को नियात्रित करने की शक्ति का 1951 के प्रयम सव-धानिक सक्षोधन द्वारा काफी विस्तार कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप व्यवसायी एव उद्योगा के राष्ट्रीयकरण का माग खुल गया है।

व्यवसाय व्यापार एव वाणिच्य सम्बन्धी स्वतः त्रता का मौलिक अधिकार स्वीकार करते के सम्बंध म सविधान सम्म के सदस्यों म काफी स देह ब्याप्त था। भायरलैण्ड एव स्विट्जरलैण्ड ही भय वा देश हैं जहाँ पर व्यवसाय सम्य भी स्वत त्रता को मौलिक अधिकार माना गया है। सविधान म तस्तम्ब धी व्यवस्या देश के जिस्त सामाजिक स्वरूप की होन्द से जिंवत ही है। मारत म व्यवसायां का आधार जाति प्रया रही है। ऐसी स्थिति म व्यावसायिक स्वतानता के लिए सर्वधानिक सरक्षण की विशेष रूप स आवश्यकता थी। वयक्तिक स्वत नताः।

संविधान के अनुसार¹⁸ किसी व्यक्ति की उस समय तक दिण्डत नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने किसी विधि का उल्लंघन न किया हो तथा अपराध के लिए किसी व्यक्ति का प्रचलित विधि द्वारा प्रस्तावित दण्ड से अधिक दण्ड नहीं दिया जा सकता। एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दो वार दण्डित नहीं किया जा सकता है। अभिमुक्त को स्वय अपने विरुद्ध गवाही दने के लिए वाच्य नहीं किया जा सकता । अनुच्छेद 21 के अनुसार व्यक्तिया को उनके जीवन एव वैयक्तिक स्वत प्रता से विधि द्वारा स्वापित यवस्या (procedure established by law) स ही विति किया जा सकता है, न कि अय किसी प्रकार सं। सविधान के मूल प्रारूप म विधि को उचित प्रक्रिया' (due process of law) द्वारा ही किसी व्यक्ति को जीवन 17 Articles 20 22 18 Article 20

एव स्वतानता सं विचत करन नी व्यवस्था थी। लेकिन बाद मे 'विधि की प्रक्रिया' ने स्थान पर 'विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था' शब्दावली का प्रयोग किया गया। प्रारूप निर्मायो परिपद ने इस परिचतन के दो नारण दिये है प्रथम, बैयक्तिक स्वतापता राब्द नेयल 'स्वत नता' शब्द की अपेक्षा अधिक निश्चित है एव विस्तृत व्यारमा सम्मव नहीं है। दितीय, 'विधि द्वारा स्थापित प्रतिया बिल्बूल स्पप्ट है। स्मरणीय है कि 'विधि द्वारा स्यापित प्रक्रिया शब्दावली' ना प्रयोग जापान के सविधान (1946) मे किया गया है, जबनि त्रिटिश एवं अमेरिकी सविधाना म 'विधि की उचित प्रतिया' बाक्यादा ही पाये जाते हैं। देश के विभाजन के पश्चात सविधान समा के अधिकाश सदस्यों में 'व्यक्तिगत स्वाधीनता' की अपेक्षा राष्ट्रीय एकता के लिए 'सामाजिक' नियात्रण' को स्थापित करने की चित्ता अधिक दिखायी दती थी। अत 'विधि की विचत प्रक्रिया' के स्थान पर 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' शब्दावली को मा यता हो गयी है। इसके फलस्वरूप अयायपूर्ण विधिया के सम्बन्ध म पायालय हस्तक्षेप करन से विश्वत हो गया है। सविधान समा ने 'विधि की स्थापित प्रतिया की दो अप कारणों से भी स्वीवार किया है। प्रथम 'विधि की उचित प्रक्रिया' वाक्यादा का अब अस्पष्ट है, द्वितीय, वे यायपालिका को तृतीय सदन नहा बनाना चाहत थे। आग्ल-सैक्शन देशा में 'विधि की उचित प्रक्रिया शादावली का निश्चित अय विकसित ही चुका है। इस अथ के अनुसार इस शब्दायली म वैयक्तिक स्वत त्रता का अमाव निहित है, जसे कि किसी भी व्यक्ति की बिना वारण्ट के तलादी नही ली जा सकती, त्याया लय म सभी का रक्षार्थ आवेदन का अधिकार प्राप्त है, नागरिको को प्रत्येक मामले म खुनी अदालत म विचार का अधिकार है और यदि कोई विधि इन व्यवस्थाओं का उल्लंघन करती है तो यायालय उसे अवधानिक घोषित कर सकती है। सक्षेप में 'विधि की उचित प्रक्रिया' से जय प्राकृतिक याय के सर्वमा य स्वीकृत सिद्धा तो से है। इन स्वीकृत सिद्धा ता के अनुसार सम्बन्धित विधि की निहित अच्छाई एव बुराई की समीक्षा की जाती है। सयुक्त राज्य अमरिका में 'विधि की उचित प्रक्रिया' शब्दावलों की क्सी पुणरूपेण परिमामा नही की गयी है। लेकिन सामा यत इसका स्पष्ट अध यह है कि प्रत्येक अमियुक्त को सफाई का अवसर दिया जाना चाहिए, बलपुवक अपराधी स अप राध की स्वीवृति नहीं ली जानी चाहिए, खुले यायालय में निष्पक्ष रीति से मुकहमा की सनवाई होनी चाहिए तथा प्रत्येक अपराधी का विधिक सहायता उपलब्ध होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त विधि उचित होनी चाहिए और मनमान ढग से निर्मित नहीं होनी चाहिए। स्मरणीय है संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाञ्च 'वायालय ने 'विधि की उचित प्रक्रिया' शब्दावली का ऐसा अथ किया था जिसके फलस्यम्प ध्रमिका एव अ य मामाजिक विधियों को सवाच्च 'यायालय न अवैधानिक घोषित किया था। भारतीय सविधान निर्माता इस प्रकार की स्थिति से बचना चाहत थे अत उ होन विधि द्वारा स्थापित प्रकियां का प्रयोग किया है इसके फलस्वरूप वैयक्तिक

स्वत नवा सम्बंधी अतिम निषम के अधिकार न्यायपालिका की प्राप्त न होकर स्वस्थापिका को प्राप्त हो गये हैं 1- उपरोक्त अनुकेव में विधि मुक्य शब्द है। विचि शब्द का इस अनुष्वेद के संदम म क्या वेष है ? रीज्य निर्मत विचि, प्राष्ट् विक्र या मौतिक विधि । सर्वोच्च पायालय के अनुसार 'विधि की स्थापात प्राप्त, आछ तात्मय राज्य विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही है ।''

वनुच्छेद 22 द्वारा स्वेन्छित गिरफ्तारी एव नजरवची से विरुद्ध यह ध्यव-त्याएँ की गयी हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को नजरव द किये जाने के शीझातिशीझ ब दी बनाये जाने के कारणो से अवगत किया जाय एवं अपनी पस व के वकील से परामध करने एव वचाव की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। इसके व्यतिरिक्त गिरफ्तारी के 24 घण्टे के जबर ही निकटस्य दण्डाधिकारी के समक्ष सम्बध्यित व दी की प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इससे अधिक समय के लिए व वी की मजिस्ट्रेट की आज्ञा पर ही हिरासत म रखा जा सकता है। ²⁰ जपरोक्त अधिकारों के यो अपनाद हैं। यह अधि हार प्रथम, जन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता है जो शतु राज्यों से सम्बन्धित होते हैं और दितीय जिह किसी निवारक निरोध विवि अधिनियम के अ तगत वादी बनाया जाता है। निवारक निरोध अधिनियम के अ तगत किसी ब दी को तीन माह से अधिक तमय तक बिना मुक्ट्मा चलाये व दी नहीं रखा वा संस्ता । लेकिन परामशतायी परिषद हारा नजरव दी के काल म वहि की सत्सुति किये जाने पर जसम वृद्धि की जा सकती है। इस प्रामचदायो परिवद म उच्च यायालय के न्यायाचीशा के समान योग्य व्यक्ति सदस्य होते हैं। सस्य को विधि बनाकर किसी भी व्यक्ति की नजरब से को बढाने का अभिकार प्राप्त है। संसद को परामखदायी परिवद द्वारा नजरबन्दिया भा प्रधान को जानभार काचा है। एएए का नामण्यामा नार्य आहे. स्वास के जानभीन सम्बाधी पढ़ित को विधि द्वारा निर्धारित करने का अधिकार है। सावजनिक हित में नजरव दी विभिकारी नजरव दी के कारणों की न बताने का अधिकार रखता है।।

भनुन्धेद 22 समझौते का परिणाम था। 'विधि को उचित प्रकिया' सन्दा वती को लकर सविधान समा के सदस्या म दो गुढ़ हो गये थे। श्री कल्हेयाला वता का एक राजवान करा । मणिकतात मुद्दी विधि की उचित प्रतिया छन्द के प्रयोग के समयक मे तो थी अल्लारी कृष्णास्वामी अध्यर 'विधि की स्थापित प्रक्रिया' के प्रयोग के समयक थे। हाँ अम्बेडकर का इस सम्बच म कोई हिस्टकोण नहीं या । निधि की स्यापित प्रक्रिया' क समयका को सन्तुष्ट करने के निए अ तत अनुच्छेद 22 म 'विधि की उचित प्रतियां की मूल धारा के स्थान पर उसे स्वीकार निया गया। 19 A K Gopalan vs State of Madras, A I R 1950 S C 27 20 अनुन्धेद 22 (1) तथा (2)

²¹ बनुच्छेर 22 (4), (5), (6) एव (7)

पारतीय ससद द्वारा प्रयम निवारक निरोध अधिनियम (Preventive Detention Act) 1950 ई म प्रारम्भ म केवल एक वर्ष के लिए पारित किया था। 1951 ई म उसे सज़ाधन अधिनियम (Amending Act, 1951) द्वारा एक वय के लिए और वढा दिया गया। इस अधिनियम द्वारा सभी नजरवारी मामला को परामदायीय पिराद के समझ विचार हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक कर दिया गया था। 1954 ई तक इस अधिनियम होता पढा बाता पहा और इस वर इस व्यागामी तीन वर्षों के लिए बढा दिया गया। इसके पश्चात 1957, 1960, 1963 एवं 1966 ई में आगामी तीन वर्ष के लिए इसकी विद्व की जाती रही है।

सविधान समा के सदस्यगण वैयक्तिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी उपराक्त व्यवस्थाओ की चर्चा करते समय अख्याधिक सचेत थे । उन्होने स्वता प्रता पर प्रतिवाध सम्बन्धी व्यवस्थाओं की तीव आलोचना की है। डा अम्बेडकर ने इन प्रतिव वा का समयन किया था। उनका मत था कि वतमान परिस्थितिया स यह आवश्यक है कि काय पालिका ऐसे व्यक्तिया को नजरब द कर जिनसे सावजनिक हित को सकट अथवा देश की सुरक्षा का खतरा उत्पत्र हा सकता हो। 23 पर तु सविधान समा इस तक से स तुष्ट म हो सकी । सदस्यों ने इसकी तीज आलोचना की । यायाधीश बख्शी टेकचाद का मत था कि ससार मे नोई ऐसा लिखित सविधान नहीं है जहा माधारण स्थित मे मुकद्दमा चलाय विना नजरवादी की व्यवस्था हो। सर्विधान का यह माग उनकी हृष्टि मे 'दमन का आरापन एव वैमक्तिक स्वतं त्रता का हता है ।' ३ डा गापीच द भागव के अनुसार यह हमारी असफलताओं का राजमुक्ट है। 24 महावीर त्यांगी 5 ने तो इन प्रतिवाधी का मुलाधिकारा का ही निवेध बताया। निवारक निरोध अधिनियमा क आतगत नजरबादिया के आकहो के अध्ययन स उपरोक्त जालीचनाओं से उत्पत्र शकाओं का एक सामा तक समाधान हा जाता है। 1950 ई म 11 हजार व्यक्ति निवारक निरोध अधिनियम के अन्तगत नजरबाद थ । 1957 ई म इनकी सख्या 205 थी जिनम से काफी व्यक्ति केवल पद्माव राज्य म ही नजरवन्द थे। परामशदायी परिपदा न एसे नजरवन्दिया म से 60 प्रतिशत व्यक्तियों की मुक्ति के आदेश दिये थे । विगत 25 वर्षों की समीत्मा से यह स्पष्ट है कि आरतीय जनता पर्याप्त वैयक्तिक स्वत त्रता का उपयोग करती है। निवारक निरोध अधिनियमा को प्रत्यक राज्य द्वारा पारित किया जाता है। अत मारत म शासन को इस प्रकार नो शक्ति प्रदान न करा। एक भूल ही होती। कुछ विचारका का यह मत है कि 21 वें

²² Constituent Assembly Debates, V, E 1529

²³ Ibid

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid p 1547

954 | बाधुनिक शासनतः त्र

वनुष्वद ने निरमतारी के पश्चात व्यक्ति को याचिक सरक्षण सं लगमग विचत ही कर दिया है। गोपण के विरुद्ध अधिकार ह

सविधान ने मनुष्यों के नय विक्रय वेगार एवं इसी प्रकार के वलपूर्वक कार तेने के जय तरीको पर प्रतिव घ लगा दिया है और इन अवस्थाओं के उल्लंघन की विधि द्वारा वण्डनीय अपराघ घोषित कर दिया है। ³² वेकिन सावजनिक कल्पाण क उद्देश से राज्य को नागरिको से अनिवाय सेवा (compulsory service) प्राप्त प्रदेश्य ए राज्य का नापारका च जानवाय चया (स्थामध्यका) क्यास्त्रा करते का अधिकार है। 14 वस से कम बायु के बातको को कारताने या खान या तिकट्यूण सेवा सम्ब भी काय म नहीं बनाया जा सकता है। ⁸ इन अनुकड़ेवा की सुबना रिका म वासता या जलपूनक प्राप्त सेना (involuntary servitude) को समाप्त कर दिया गया है। मारत म हरिजनो या अछूनो से बेगार ती जाती थी। यह व्यवस्था ताम ती प्रुप का अवशेष तथा शोषण का कुत्सित रूप थी। यम के नाम पर देनवासी मया प्रचलित थी। सर्विधान निर्माता इन स्थितियों को समाप्त करने क लिए इत सम्मन्द थे। इनके रहत हुए 'विधि के समक्ष समानता तथा स्वत जता' के अधिकारी का कोई मुख्य नहीं या। कम आयु के बातको स मारी एवं सकटपूर्ण वेवा लेना अमा नवीय शोपण है। इससे वालको का विकास रक नाता है वे आवरण अटट हो जाते है एव अपराचों की तरफ उम्रुख होते हैं। अत ये व्यवस्थाएँ वाद्यतीय है और लोक-

इस अधिनियम के अंतगत सभी व्यक्तिया को सावजनिक व्यवस्था, सदाचार एव स्वास्थ्य तथा इस वृध्याय क अप्य भावधानो के अधीन अन्त करण की स्वत नवा तथा किसी धर्म को अवाध रूप स मानन, जाचरण करने एव प्रचार करने की समान स्वत नता प्राप्त है। वेकिन इस प्रवस्था का किसी वतमान विधि के प्रवतन पर कोई विपरीत प्रमान नहीं होगा और न राज्य हारा किसी भी आधिक नित्तीय एवं राज निर्माण का निर्माण करने वाली विधियों के निर्माण पर या हिन्दुआ की सावजनिक धामिक सस्याओं को हिं हुआ के चेप क्षमी वर्गों के लिए खोजने पर ही कोई प्रतिव प होगा। इस सरम म विक्लो, जैंगी एवं वीदो, संगी को हिनुसा के

²⁶ Right against exploitation (Articles 23 28) 27 अनुच्छेद 23 (1)

²⁸ अनुस्केद 23 (2) और अनुस्केट 24

²⁹ Right to freedom of religion (Articles 25 28)

अत्तगत ही मानने की व्यवस्था है। सिनखो को कृपाण घारण करने एव उसे लेकर

प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसाउप सम्प्रदाय को सावजनिक व्यवस्था, चलने का अधिकार प्रदान किया गया है।³⁰ सदावार एव स्वास्थ्य के अभीन (अ) धार्मिक और दान कार्वों के लिए धार्मिक सस्याओं की स्थापना एवं उनके संचालन, (व) धार्मिक कार्यों के प्रव ध, (स) स्थामी एव अस्थापी सम्पत्ति के अजन एव स्वामित्व, तथा (द) विधि के अधीन ऐसी सम्पत्ति पुन जरनाना जन्मात र जना पुर रचाराचा पूना (च) जना व जना पुरा प्रसास को ऐसा कोई की देखमाल करने के अधिकार प्रदान किये गये हैं | शिक्षी मी व्यक्ति को ऐसा कोई का बचनाच करून के जानकार जवान एक नव हु। त्याच ता ज्यास का प्यास का प्रवास का सकता जिसकी आय किसी घम विशेष या सहप कर देने के लिए वाध्य नहीं किया जा सकता जिसकी आय किसी घम विशेष या सहप्र दाय की उन्नित या व्यवस्था के लिए विशेष रूप स विनियुक्त कर दी गयी है। राज्य विधि के अधीन पूगत या आधिक रूप ने सचातित किसी शिक्षण सस्या ने कोई पामिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन यह व्यवस्था उन शिक्षण सस्याओ पर लागू नहीं होती है तो राज्य प्रशासन य होते है परन्तु जिनकी स्थापना किसी धार्मिक तार पट्ट क्या हुआ की जाती है और ऐसी सस्याओं में धार्मिक शिक्षा की छूट है। वन ना नार अपन ना नार हुना पुरुष प्रत्यान जनाता । वना ना पुरुष हुन इसके अतिरिक्त राज्य से मा यता एवं आर्थिक अनुदान प्राप्त किसी भी शिक्षण सस्या बार जाता पर किया में धार्मिक शिक्षा या वार्मिक उपासना में मांग लेते के तिए था चत्रक चत्रका रचार व वस्त्रक काला व वस्त्रक काला व वस्त्रक व्यवस्थाएँ दूण अभिक किसी विद्यार्थि को बाध्य नहीं किया जा सकता है । अ उपरोक्त व्यवस्थाएँ दूण अभिक स्वत प्रता का आश्वासन देती हैं और धम निरपेक्षता का आधार है। राज्य धम के सम्ब थ मे तटस्य है। लोकतात्रिक समाज मे धम निरपेक्षता लोकतात्रिक समाज तान्व व न प्रभाव व र प्रमास से मुस्सिम साम्प्रदायिकता के ताण्डव नत्य का दु खद निरपंक्ष आरतीय लोकत न के स्थापनाथ उपगुक्त प्रावधाना की व्यवस्था की गयी है।

भारत में निवास करने वाले नागरिकों के प्रत्यक भाग की जिनकी अपनी भाषा, सास्कृतिक एव शिक्षा सम्ब घी अधिकार्यः तिथि एवं सस्कृति है, उह उनके सरक्षण क अधिकार प्राप्त है। अ किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा स्वातित या सहायता प्राप्त विक्षण संस्थाता म धम, मूल, बद्दा, जाति, का भाग अपने करण प्रकार कर भए व्याप अपने अभाग विश्व तथा है। विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश मापा अपनी इनमें से किसी आघार पर भी प्रवेश से नहीं रोका जा सकता । असी

³⁰ बनुच्छेद 25 (1) (2)

³¹ अनुच्छेद 26

³² अनुच्छेद 27

³⁴ Cultural and Educational Rights (Articles 29 30)

³⁵ अनुच्छेद 29 **36 अनु**च्छेद 29 (2)

धार्मिक या भाषायी अल्पसंस्थकों को अपनी शिक्षण संस्थाएँ स्थापित करने का अपि कार है और राज्य ऐसी किसी संस्था के साथ अनुदान देने में यम या मापा के आधार पर किसी प्रकार का कोई मेदमान नहीं करेगा। अ जपरोक्त प्रान्धानों के माध्यम से पर किया अकार पा कार भवनाव पहा करना। व्यवस्त अवस्तान क पालन व अल्पसंत्यको के हिंतो का संरक्षण किया गया है तथा च है अपनी मापा, धम, निर्मि एव वर्षात्रका है हिसाम विस्ताम संस्थार स्थापित करने एवं जनके प्रवास करने के अधिकार परहरू में भाग क्षिम क्षित क्षेत्र प्रमाय भूषा द्व व्यक्त के मुस्स में भाग क्षेत्र भाग क्षेत्र में क्षेत्र के स्व दिय भय है। इस सम्ब व भ एक जायात है। जायाचा जारपादनका का अधिकार दिया जाना समक्ष में जा सकता है पर तु धम के आधार पर परताम का लावकार विवास माना चनक न जा वक्ता है । सारतीय इतिहास रवनम् प्रस्तामः का प्रवासम् राष्ट्रीय एकता विरोधी सकीण साम्प्रधायकता का गढ बनी है और बनगी। सम्पत्ति का अधिकार्

सविधान सम्पत्ति कं अधिकार को स्वीकार करता है और किसी मी व्यक्ति को विधि की सत्ता के विना उसकी सम्पत्ति से विचत नहीं किया जा सकता। 19 साव का विश्व को विद्या की सत्ता के अधीन ही सम्मति को सतिपूर्ति किये जाने पर अनिवायत हस्तगत किया का सकता है। राज्यो द्वारा सम्पत्ति को हस्तगत करने जानवाचा वृत्त्वपत । भवा जा सकता है। राज्या श्वारा वाचात का वृत्त्वपत को स्वीकृति क्ष लिए प्रस्तुत की जाती हैं एवं उसके प्रस्तात ही व प्रमाची होतो है। यह व्यवस्था देश म इस प्रकार की विधियों में एकल्पता एव पा जाता एक हराद जाराजा का जाता जा का का की हिस्स से की हिस्स से की गयी हैं।

'सम्पत्ति का अधिकार' सबसे अधिक विवादास्पद रहा है और सर्वोडच याया तय के समझ सम्मति के अधिकार सम्बन्धी विवाद ही सबसे अधिक सरमा म पहुँचे त्व म वनस्य प्रत्याम् म जावमार प्रन्त था त्वाब स्व प्रवच जावम पर्या म म्हर् भी हैं। संविधान के दो अनुक्छेद 19 एवं 31 सम्पत्ति से सम्बन्धि हैं। अनुक्छेद 19 मा हा सावधान क दा अनुच्छद 12 एवं 31 सम्पात संस्था पत हा अनुच्छद 12 क द्वारा एक प्रकार से 'सम्पत्ति की स्वतानता' की व्यवस्था की सभी है। अनुच्छद 31 द्वारा तम्पत्ति क अधिकार को राज्य द्वारा हस्तगत करने की व्यवस्था की गयी है और उस पद्धित का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार राज्य किसी व्यक्ति को उसकी सम्मत्ति से वित्त कर सकता है। राज्य द्वारा वैयक्तिक सम्मत्ति के अनिवायत हत्त पत करने की अवस्था म यद्यपि संविधान सितिपूर्ति की व्यवस्था करता है परे दु सित इति के यायपूर्ण (fair) एवं समुन्ति (equitable) होने के सम्बंध म भीन हैं। र्रात क नावहर विकास के कि स्वित्त्रित होंगी परन्तु स्वित्रित की राधि एव वास्त्रात्त के सिद्धान्ता को निश्चित करने का अधिकार विधानमण्डल को दिया 37 अनुच्छेद 30

³⁸ Right to Property (Articles 31, 32A and 32B)

गया है। उचित एव यायपूण शब्दों का प्रयोग जानबुक्त कर छोड दिया गया था क्यो कि इन शब्दों के प्रयोग से मुकदमेवाजी के बढ़ने की सम्मावना थी । क्षतिपृति के बौचित्य एव अनौचित्य पर विचार करने का अधिकार यायपालिका को न देकर विधान-मण्डल को दिया गया है। 'यायालया को केवल उसी अवस्था में हस्तक्षेप करने का अधिकार है जबकि सम्पत्ति को हस्तगत करने वाली विधि क्षतिपूर्ति की कोई व्यवस्था न करती हो या उसके द्वारा नाममात्र की क्षतिपृत्ति की व्यवस्था की गयी हो । क्षतिपृत्ति सम्बाधी सबैधानिक व्यवस्था शरणार्थी-सम्पत्ति पर लागू नही होती है। कुछ मामलो में क्षति-पूर्ति की नाममात्र की अवस्था म वायालयों के हस्तक्षेप पर प्रतिबाध लगा दिया गया है, उदाहरणाथ, कुछ विधियो के विरुद्ध क्षतिपूर्ति सम्बन्धी वैधानिक व्यवस्था के उल्ल-धन के आधार पर यायालय म कोई जापत्ति नहीं उठाई जा सकती है। ये विधियाँ हैं (1) सविधान के फिया वयन के समय विधानमण्डल के विचाराधीन विधेयक तथा पारित होने पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों के लिए सुरक्षित विधेयक¹⁰, (11) सविधान के किया दयन के 11 वप पर पारित विधियाँ एवं नवीन सविधान के कियान्वयन के तीन माह के अंदर राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत एवं प्रमाणित विधियाँ। 41 सविधान समा की वहस के दौरान यह स्पष्ट हो गया था कि उपरोक्त प्रावधाना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्रास आदि राज्यों के जमीदारी जन्मलन विधेयकों की सरक्षण प्रदान करना है।

पर त झतिप्रति सम्बाधी उपर्यक्त कठोर प्रावधानी की व्यवस्था जमीदारी जाम-लन विधेयको की पायालयो के हस्तक्षेप से रक्षा न कर सकी। पटना उच्च पायालया ने सवसम्मति सं कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य⁴² विवाद मं निणय देते हुए विहार जमीदारी उपलन विधेयक (1950) को असवैधानिक घोषित किया था। 18 उच्च याया स्य ने इस निणय में यह मत व्यक्त किया था कि क्षतिपूर्ति के प्रश्न के परीक्षण का अधिकार पायालय को इस इप्टिसे प्राप्त है कि सम्बर्धित विधि द्वारा अय मौलिक जिकारो सम्बाधी प्रावधाना-यथा, अनुच्छेद 14 (समता के अधिकार)-का अति-श्रमण तो नही होता है। विहार जमीदारी उम्मलन विधेयक को जिन आधारो पर उच्च यायालय ने अवैधानिक ठहराया था उन्हें सर्वोच्च यायालय ने उचित माना था। 144

⁴⁰ अनुच्छेद 31 (4)

⁴¹ अनुष्छेद 31 (6)

⁴² Kameshwar Singh vs State of Bihar

⁴³ परत् इलाहाबाद उच्च यायालय ने उत्तर प्रदेश अमीदारी विषेयक एव नागपूर उच्च यायालय ने सी पी (Central Provinces) जमीदारी विधेयक को वैध घोषित किया था।

[&]quot;Article 31(4) does not bar the jurisdiction of the court from enquiring whether the law relating to compulsory acquistition of property walid to see whether the acquisition has been made for a public purpose

. उत्पक्त शासनत त्र

इस प्रकार के यायिक हस्तक्षेप को मनिष्य मं रोकने के लिए प्रथम सनभानिक ससी धन (1951) हारा सिवधान म संशोधन कर दिया गया और अनुच्छेद 31 म 31 (अ) पत (12) अरा वापवान न वर्णायन मर विवा मवा जार वाउण्टर अ न अर्था पत अर्थायन मर विवा मवा जार वाउण्टर अन्य राज्य राज्य (Ninth Schedule) संयुक्त कर दी गयी।

अनुच्छेद 31 (अ) के ह्वारा यह व्यवस्या की गयी है कि राज्य ह्वारा किसी रू सम्मति (estate) को हस्तमत करने या हस्तमत मू सम्मति के अधिकारों की सम ते भारत (ज्वास्त्र) मा श्राम्यक भारत वा श्राम्यक त्र प्रभाव के भारत के समय किसी सम्पत्ति का सावजनिक हित में या उन्हें समय लिए उचित प्रवच हेंचु तसका प्रवच अपने हाथा में लेने या दी या अधिक निवमा व संयुक्त करने आदि के अधिकार प्रदान करने वाली विधि को इस आधार पर अवधा पद्मा करण जाम के जानकार जनाम करण नाम का के जामर मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करती है।

वनुष्छेद 31 (व) के द्वारा नवी अनुसूची जोडी गयी है और इसमे जन विधियों का उल्लेख किया गया है जिनकी वैधता को किसी भी यायालय में किसी प्रकार की कोई बुनोती नहीं दी जा सकती और वे विधियाँ किसी पायात्व के प्रति कूल निषय या आदेश के होते हुए मी वह घोषित की गयी है। इन दोनो अनुक्छेंद्रो हुँ भारत का भारत का शाम हर का कर का का भारत है। का का का के सम्बन्धित सभी विधियों पायासम के सेनाविकार से स्वत न हो गयी है।

वैविन प्रथम संबंधानिक संबोधन सं समस्या का समाधान नहीं हुआ। शी ही यह अनुभव किया जाने लगा कि जभीदारी विधिया के अतिरिक्त अस प्रकार के हा वह जनुनव काम जान जान जान का जाना है। इस्तिमत के हस्तामत करत के सम्बन्ध में शिविप्रति का प्रश्न किर मी विवसमा है। धोलापुर स्वितिम एव बीबिम मिल को सरकार ने अपने नियंत्रण में से लिया मा । कारलाने का प्रवच बहुत बुरी अवस्वा म चा और प्रवच मण्डल हारा अपनी धालियों कारकार का अब व बढ़ा उदा अपरण न ना आद कव व नण्या आदा अपरा कार्य का दुरुपयोग् किया जा रहा था। अगस्त 1949 ई. म किसी पूब सुबना के बिना ही का बहर मिल को बद कर दिया गया था जिसके फलस्वक्य 13000 मनहर वनक बारा भाग का व के कर भिषा भाग का विकास के विसास हो गये है। सर्वोच्च गायालय ने बोलापुर मिल सम्बन्धी इस विवास म वराजगार हा गथ था छन्। प्रवास्त्र वर्णानास्त्र मानास्त्र मानास्त्र वर्णानास्त्र मानास्त्र वर्णानास्त्र के निषय को परिवृत्तित करते हुए 1953 ई में इसरजेसी वेन्ध्र उच्च पावालय का मान्याव का पार्यावत करत हुए 1955 है से अवस्य भीवीजन्म आँडीने से 1950 है को अवस्य भीवित किया स्थाकि उसम समुच्ति स्था भावाजनस्व भावातः । १२८० ३ का जवव पापव क्वाच प्रधाक व्यव प्रधाक व्यव प्रधाक व्यव प्रधाक व्यवस्था नहीं की गयो थी । इस विवाद मं सासन ने यह तक प्रस्तुत किया द्वात का व्यवस्था वहा का भवा था। इस प्रथाद क शासन न यह वक्त अस्पूर्व प्रथा भा कि जिसने नेवल मिल के प्रवास को अपने हामा मू ने लिया है जब स्वित्रति का था १क जनम प्रवास मान के अब व का जनम हाथा के पायबा है जन जान्यूस है। सर्वोच्च यायास्य ने राज्य के द्वारा चीतापुर मिन नेत्र चरान्न हा गहा हाता है। प्रवाश्च वावायव न संबंध के हो से चालापुर भाष को अपने नियानम्म केना अनुन्देद 31 (2) के निषरीत माना और जावन के हसे हास को अथम ।मध्य त्रण म धमा अपुण्यत अर (८) क ।वपस्त भागा वर्गर् पादाम क वच ना मो अवसानिक मोपित बर दिसा। इस निषम के बडे दुरमामी परिणाम हुए। उदि यान म संशोधन हेतु चतुय संशोधन अविनियम (1955 हैं) पारित निया गया और

31वें अनुष्केद में एक नवीन उपघारा 2 (अ) बोडी गयी। इसके द्वारा निम्न व्यव स्याएँ की गयी

- (1) अनिवायत हस्तमत की जाने वाली सम्पत्ति की क्षतिपूर्ति की घनराशि या तस्तम्ब पी सिद्धान्त को राज्य निर्धारित कर सकता है तथा सम्पत्ति का अनिवायत हस्तगत करने वाली विधि का अपर्याप्त क्षतिपूर्ति के आधार पर यायालया मे चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- (2) शासन द्वारा जब किसी सम्पत्ति के स्वामित्व या तरसम्बाधी अधिकार प्रहण नहीं किये जाते हैं अधितु राज्य केवल प्रवाध सम्बाधी निया गण ही अपन हाथा में तेता है, जैसा कि घालापुर वीविंग मिल के सम्बाध में तिया था, तो यह सम्पत्ति का अनिवाध हस्तणत करना नहीं माना आयगा और एसी अवस्था म किसी प्रकार की क्षतिप्रति का कोई प्रस्त उत्पात ही नहीं हो सकता।
- (3) प्रथम महाधन के द्वारा जमीवारी उम्मलन विधियों के 9वी सूची में शामिल करके जह "यामिक हस्तक्षेप से सरसण प्रवान किया गया था। इस मूची म 6 अग्य विधियों को और जीव दिया गया और उनकी पूण सरवानिक सरसण प्रवान कर दिया गया। सक्षेप में, सम्मति सम्बंधी ऐसी विधियों को जिनके द्वारा राज्य किसी सम्मति को अतिवायत हस्तमत करने या उसकी सम्मति म परिवतन की व्यवस्था, कुछ समय के लिए सुप्रव वे हुँद सम्मति को हस्तगत करना या दो या अधिक निगमा का एकीकरण करना या जो प्रवाचका, अनिकर्ताओं सचिवा या निगमों के प्रव धको एव हिस्सेदारों के मतदान अधिकार को सीमित या समान्त करने की व्यवस्था करती हो, त्यायालया में चुनीठी नहीं दी जा सकती। इसके अविरिक्त जवधि के पूर्व खिनज पदाध या तेल के ठेको या जाउसे सा समक्षीता को समान्त करने या उनम परि वर्तन करने वाली विधिया की वैधानिकता को या यायालया म चुनीती नहीं दी जा सकती है। यायालया म चुनीती नहीं दी जा समन्ती है।

सम्पत्ति के अधिकार को सीमित करन बाला तीमरा महत्वपूण मवैधानिक सशोधन 17वां सत्तोवन है। इसके द्वारा अनुच्छेद 31 म प्रमुक्त द्वारा 'estate' का अप परिवर्धित कर दिया गया और उसके क्षेत्र को विस्तृत करता हुए भूमि मुधार अधिनियमों के अधीन अने वासी रेसनाडी एवं अप प्रकार को जू सम्मत्ति को जी उसम शामिल कर निया है। 'भू सम्पत्ति' (estate) सब्द के अप के सम्याप म रहन विवाद के कारण दम सताधन को पारित करने की आवश्यकता उत्थत हुई थी। सर्वोच्या पायालय ने एक विवाद की विवाद के तिया है । धी स्वाद की अधिन या स्वाद स्वा

⁴⁵ कु होमोहन बनाम केरल राज्य।

श्लीम को उन क्रमको के मध्य विवरित करने की व्यवस्था की गयी थी जिनके पास तियाँदित वीमा सं कम श्रुमि थी तथा श्रुमि की उच्चतम सीमा निर्यादित कर सी थी। पर लागू मही होता था। सर्वोच्च यायालय के अनुसार उक्त विधेयक अनुस्थेद 14— पर जात्र गर्धा हाता था। त्याच्य वायावय भ अनुवार एका व्यवस्था भ अनुवार एक व्यवस्था भ अनुवार एक व्यवस्था भ अनुवार 17वा संशोधन कर दिया। इसके द्वारा निम्न व्यवस्थाएँ की गयी हैं

- (1) राज्य द्वारा सम्पत्ति को अनिवायत हस्तगत करने पर उसे अतिपूर्ति की क्षप्रणता के जाधार पर यायालय म बुगोती नहीं दी जा सकेगी। बेनुक्छेद की प्रथम विषारा म तत्सम्बची एक व्यवस्था संयुक्त कर बीगयी।
- (2) अनुब्हिद 37 (2) (a) म एक नयी उपघारा जीडकर महास एवं केरल राज्यों में (1) जागीर, हनाम, मुखी एवं हमी मुकार की अस्य जनेक भूमियों एवं (11) रवतवाडी व दोवस्त के अधीन श्लीम को भी श्लू संस्पृति के अत्यत भागा राम (11) प्रतावादा व बावरण क जवान ज्ञान का ना ज्ञ चन्नाच क न प्राचित्र के सुबी म जावस्थक परिवतन किये गये और 144 राज्य प्रसि युवार सम्बची निर्मयक्ता को जसम् शासिल किया गया। इससे इन विधियों को यायात्यों के हस्तकेप स सरक्षण प्राप्त हो गया।

सम्मत्ति व अधिकार म जपरोक्त संशोधनो की यह कहकर तीत्र वालोचना की गयों है कि सम्पत्ति के अधिकारों को आप्त चारिक सरक्षण समाप्त ही गया है। इस आलोचना का परीक्षण गीलकनाम विवाद म हुआ था।

गीलकनाथ विवाद-9वी सूची म जोडे गय उपरोक्त विधेयको म से बो पालकार विवाद— प्रशास पाड पर परस्ता प्रथमण प प विवास की मोलकनाय एवं अप ने तीन यायिक माननाओं के माध्यम से याया विभवका। का भाषकनाथ एव ज व न तान थायक याचनाला क भाष्यम त थाय त्य म चुनोती दी गयी। ध्व लेकिन उक्त विशिया की वैधानिकता का परीक्षण याया त्य म चुनाता वा नवा। जामण ज्या व्यावका का प्रवासका का प्रावस का प्रवास के विद्या जो सकता था जब तक कि 17वाँ सबपातिक पथ शरा जा तथ्य एक गर्थ (भ्रम्बा जा क्रम्बा व्या व्यव एक एक अपना क्रम्बा व्यवसाय क्रम व्यवस्था क्रम प्रधावन वर्ष भा का कार्यक्ष वर्ष प्रधानम् का उत्तर का स्थानम् का अपने का स्थानम् वर्षे प्रधानम् वर्षे प्रधानम् भौतिक अधिकार पवित्र है एवं अतुन्देव 368 के अभीन भारतीय संसद को मीतिक वाबकारा का चामण का ज्याना है हैं और सविधान के अनुस्केद 13 (2) के अनु

⁴⁶ Article 31(2) (a) reads—"Where a law does not provide for the Article 31(2) (a) reages—"Where a law does not provide for the transfer of ownership or right to possession of a property to the transfer of ownership or right to possession of a property to the state of to a Corporation owned and controlled by the State, it State or to a corporation owners and controlled by the state, as stall not be deemed to provide for the compulsory acquisition or controlled by the state, as the controlled by the state of the compulsory acquisition or controlled by the state of the controlled by the state of th acquaitioning of property, notwithstanding that it deprives any

Punjab Security of Land Tenures Act, 1953 and Mysore Land 48 Golaknath vs State of Panyab A I R 1967 S C 1543

सार जो विधि मौलिक अधिकार के विपरीत है वह अवैध है। अत जो सवैधानिक सशोधन मौलिक अधिकारों का जितकमण करते है वे भी अवैध है। इसके विपरीत शासन ने यह तक प्रस्तत किया था कि सबैधानिक संशोधन की बैधता का कोई प्रश्न उत्पत्र नहीं होता क्योंकि सर्विधान का कोई ऐसा भाग नहीं है जिसम कि अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन न किया जा सके। मुख्य वायाधीश की अध्यक्षता म सर्वोच्च "यायालय के 11 "यायाधीशो की पूरी पीठ ने इस विवाद सम्बन्धी पक्ष एव विपक्ष के तर्कों को सुना या । मुख्य यायाधीश श्री सुब्बाराय ने मौलिक अधिकारी को विशिष्ट स्थान देते हुए ससद के अधिकार क्षेत्र से परे घोषित किया । यह निणय 6 5 के बहमत स दिया गया था। अनुच्छेद 368 के अधीन सशोधन पद्धति को विधायी प्रक्रिया घोषित किया गया और उसे अनुच्छेद 13 (2) के द्वारा निर्घारित सीमा के अधीन माना । फलस्वरूप प्रत्येक सर्वेधानिक संशोधन को विधि मानते हुए सर्वोच्च पायालय ने यह घोषणा की कि अनुच्छेद 13 (2) का अतिक्रमण करने वाली समी विधिया अवधानिक है। अत 17वें सवैधानिक संशोधन को भी अवैधानिक उहराया गया। इस प्रकार सर्वोच्च 'यायालय ने शकरी प्रसाद⁶⁹ एवं सञ्जन सिष्ठ⁵⁰ नामक दो विवादा में दिये गये अपने पूर्व निणया को बदल दिया । इन दोनो विवादों में सर्वाच्च लय ने मौलिक अधिकारी विरोधी सबैधानिक सशोधन की वैधता को मा यहा प्रदान की थी। इन निणयो का आधार यह था कि अनुच्छेद 13 (2) के अन्तगत प्रयुक्त शब्द 'विधि से अथ सबैधानिक विधि से नहीं हैं। 368वें अनुच्छेद में केवल सबै-धानिक संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसके द्वारा संसद को संशोधन करन की इस्ति प्रदान की गयी है। गोलकनाथ विवाद के निणय ने ससद को सवधानिक सद्यो-धनो द्वारा मौलिक अधिकारा मे परिवतन करने पर प्रतिवाध लगा दिया। पर त् सर्वोच्च यामालय न अपने निणय म 1950 ई से 1967 ई तक हए समी सवधानिक सहोधनो को वध मानने की घोषणा की । स्मरणीय है कि इस बीच म जमीदारी उ मूलन एव भूमि सुधार सम्बाधी अनेक विधियाँ पारित की गयी थी। यदि गोलकनाथ विवाद म दिया गया निणय पहले से ही प्रमावकारी होता तो देश म अव्य-वस्था फल जाती और अनक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती।

गोलकनाय विवाद के निषय के फलस्वरूप सामाजिक याय एवं आर्थिन विकास सम्बन्धी विधिया के निर्माण पर रोक लग जाना स्वामाविक या। इसक अति रिक्त यायपाजिका की शक्ति संसद की तुलना मं वृद्धि हो गयी थी। जनता द्वार विद्याल की तीन्न आलोचना की गयी। सर्वाच्च यायालय ने गोलकनाय विवाद क पदचात वका के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी विवाद मं निषय देतेहुए कहा है कि बेन। माजिका

⁴⁹ Shankarı Prasad Singh Deo vs Indian Union, A I R 1951 5

⁵⁰ Sajjan Singh vs State of Rajasthan

को वेका क राष्ट्रीयकरण र विए बानार मुल्य पर प्रण शतिपूर्ति की जानी सिहए और उन्हें सास (Boodwill) की भी दाविपूर्ण प्राप्त की भी चाहिए। संसद-संसद आर ७ व वास (Boowmin) राजा जावताल आज वरणा जावर राजा के मीनिक अधिकारा को सीमित करन मम्ब भी एक विश्वप मस्ति दिया था। इस स्थिति रा बचल एव ही समापान या कि संविधान की संवीधन करक मोतवनाय विवाद क्र निषाय को निष्माची कर दिया जाय। का मध्यान अर्थान अर्था 24व एव 25वें सवधानिक संचाधन प्रस्तुत किय गय ।

24वं सत्तोपन (1971) द्वारा समद को मौतिक अधिकारा सहित सविपान म त्रयोधन करने की सिक्ति प्रदान की गयी है। जीक्य 368 सिंपान म मसीपन एक उत्तरी प्रतिया - होना को इस प्रकार संशोधित विषा गया कि मीतिक अधिकास म मी इस जीति से पित्रवतन एवं महीधन सम्मव ही सके। संतीपन इत्तर यह भी ध्वस्था हो गयो कि समन व दोना महना हारा महोपन प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्र पति को उस अपनी क्वोह ति अनिवासन प्रदान करनी चाहिए। ससद का अपनी सव पानिक शक्ति क अतमत सविधान व विसी भी माग या अनुष्टेद का निर्मारित प्रक्रिय में सनोधित या वरिवतन करन का अधिकार भी प्रवान निया क्या और सम्पानिक संगोधन व अनुस्कृष 13 के विषयीत होने पर भी उस पायत्वस्य और अवसानिक घोषित उरत पर प्रतिवाध लगा दिया गया। इस समोधन हारा 368ई अनुचीत है तीयक म मी परिवतन कर दिया गया। भूत सीयक विद्यान को संसाधित करने की प्रतिया को विस्तिति करते हुए उत्तका सीयक 'सनियान में संसीयन एवं उसकी प्रक्रिया को संवाधित करने को संसद की शक्ति रख निया है। 25व सवधानिक संसाधन के द्वारा निम्न ध्यवस्पाए की गयी

(1) राज्य को सावजनिक जहरूव में अनिवायत हस्तवत किसी सम्पत्ति वस्त्र प म बाजार-वर सं शतिवृति दना भावस्यक नहीं है। ससद या राज्य विधानमण्ड तन्त्र व म बाजारन्दर व कावश्राव करा नावश्यक गहा है। वचद वा राज्य स्ववास्त्र करी की विधिया को अविम क्रम शतिप्रति निर्धारित करने की अधिकार दिया गा है भारताचा भारता क प्रमाण भारता के आधार पर किसी विधि का यावालय म जुनीती नहीं दी जा सकती है।

(2) किसी भी विधि को जिसके द्वारा अनुकाद 39 (व) एव (स) म निहित राज्य के मीति निवसक तत्वो मन्यूषी नीति के क्रिया वयन की व्यवस्था की गयी है। त्रिय के गात त्रिक्षक तत्था ज्ञान वा गात क त्रिक्ष वक्ष का व्यवस्था का वस्त स्थ अनुक्छेद 14, 19 एवं 31 के विष्यति होने पर अनुकछद 13 के वधीन अवस्था का वस्त स्थ गहीं किया ना सकता। प्रत्येक ऐसी निधि के साथ यह प्रमाणपत्र सन्तम होना बाहिए कि विधि नीति निर्देशक तत्व सम्ब भी नीति को किया कि करने के उद्शय से निमित्त की गयी है। राज्यो द्वारा निमित सभी विधियों को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु अनि-वायत प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गयी है।

इस सम्मानिक समीमन की तीव बालोचना की गयी। इन दोनो संचीमनो होरा गोलकताय विवाद के निषय के श्रुव को स्थिति को पुन स्थापित करने का प्रयत्न

किया गया है। जो लोग सम्पत्ति के अधिकार को पवित्र एवं अनुल्लघनीय मानते है उनको इन व्यवस्थाओं सं अस तब्द होना स्वामाविक है। सावजनिक हित में राज्य द्वारा सम्पत्ति को हस्तगत करने के अधिकार को सभी स्वीकार करते हैं। क्षतिपति का प्रश्न विवाद का विषय है। एक तरफ तो बाजार दर पर श्रतिपूर्ति दिये जाने के सम-थक हैं तो दूसरी तरफ साम्यवादी एव उग्र समाजवादी हैं जो क्षतिपूर्ति देने के विल-बुल विपरीत है।

मवधानिक उपचारो का अधिकार 1

सविधान में केवल मौलिक अधिकारा की व्यवस्था उनकी रक्षा के अभाव मे मुल्यहीन है। सविधान के जनुच्छेद 32 के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकारो के रक्षाय उचित पद्धति के अनुसार सर्वोच्च यायालय म आवेदन का अधिकार प्राप्त है। इन अधिकारो के रशाय सर्वोच्च यायालय को विमान आदेश (Writs)-बादी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)52, परमादेश (Mandamus)53 प्रतिपेध (Prohibition)54, अधि-कार पुच्छा (Quo Warranto) एव उत्प्रेपण (Certiorari) - जारी करन का

51 The Right to Constitutional Remedies (Art 32)

52 बादी प्रत्यक्षीकरण का अथ 'सदारीर उपस्थित करना है। ब्रिटिश विधि के अनु सार जन्चित रूप से बादी बनाये गये व्यक्ति को इस आदेश के आधार पर मुक्ति पाने का अधिकार है। ब्रिटेन मे 14वी सदी म इस आदेश का उल्लेख मिलता है। 1679 ई मे तो ब्रिटिश ससद ने Habeas Corpus Act पारित किया था। प्यायालया द्वारा इस जादेश को जारी करने की शक्ति को ब्रिटिश जनता स्वत-नता के लिए आवश्यक मानती है। मारतीय सविधान द्वारा व दी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी करन का अधिकार सर्वाच्च एव उच्च यायालय को प्रदान किया गया है। इस जादेश का उद्देश्य मात्र यही है कि अनुचित रीति से बादी बनाय गये व्यक्ति की मूक्त किया जाय।

53 परमादेश (Mandamus) का अब है कि 'हम आज्ञा देते है (we order) । इस प्रकार के समादेश के अधीन सर्वोच्च यायालय या उच्च यायालय किसी व्यक्ति या निकाय को उन कार्यों को करने का आदेश दे सकते हैं जो उनके कतव्य होते है।

54 प्रतिषेष (Prohibition) का आदेश सर्वाच्च या उच्च यायालयो द्वारा अधीनस्थ 'यायालयों के प्राकृतिक विधि के विपरीत कार्यों को रोकने के लिए उनके नाम

म जारी किया जाता है।

55 उत्प्रेषण (Certiorari) का आदेश भी अधीन न्यायालया द्वारा अधीनस्य "याया-लयों के नाम में जारी किया जाता है। इसका प्रयोग किसी विवाद की अधीनस्थ "यायालय स उच्च "यायालय मे हस्तान्तरित करने के लिए भी किया जाता है। इसका प्रयोग ऐस निणया को समाप्त करने के लिए किया जाता है जो सम्बधित यायालय के क्षेत्राधिकार के व तगत नहीं होते हैं जथवा प्राकृतिक याय क विप-रीत होते हैं। यह एक अत्यन्त प्राचीन आदेश है।

56 अधिकार पुन्छा (Quo Warranto) का आदेश भी पराना है। इसका शाब्दिक

अधिकार प्राप्त है। जय यायालया ना इन बादशा को जारी करन की शक्ति प्रदान करने का अधिकार अनुब्धेद 32 (3) क अधीन ससद की प्रदान किया गया है। बा अम्बेडकर के अनुसार, अनुच्छेद 32 की उपरोक्त व्यवस्थाओं के द्वारा मौतिक अधि कार को यथान रूप प्रदान किया गया है। 'यह अनुब्छेद सविधान की आत्मा एव हुदय है। " सविधान म मर्वाच्च 'याया नय का 'आवेश (Writs) जारी करन का अधिकार दक्र मौलिक अधिकारा की रूपा को सम्बन्ध व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार सविधान द्वारा मर्वोच्च पायालय को मौलिक अधिकारा का सरक्षक बनाया गया है। सर्वोच्च 'यायालय को इस सम्बाध म मौलिक या प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यह आवश्यक नहीं है कि मौलिक अधिकारा क रक्षाय पहल उच्च न्यायालय म ही अविदन किया जाय । सीधे मर्वोडन पायालय म भी आवदन-पत्र दिया जा सकता है। " विशेष परिस्थितिया म सर्वधानिक उपचारा के अधिकार को निलम्बित किना जा सकता है। " इस प्रकार की तीन विशेष परिस्थितियाँ हैं--बाह्य आक्रमण, आ उ रिक विद्राह एवं राज्या में सवैधानिक सासन की असफलता। इन स्थितिया में राष्ट्र-पति ना सकट-काल की घाषणा करन का अधिकार है एवं राष्ट्रपति मीलिक अधिकारा के रक्षाय यायिक वयचारा के अधिकार की सकट काल के लिए तिलम्बित कर मस्वा है। " सक्ट काल म राज्य की स्वतायता के अधिकार-अनुबद्धेद 19 क द्वारा प्रवत स्वत वताएँ-को सीमित करने का अधिकार है। सकट काल की समान्ति पर ऐसे प्रतिव घ स्वत ही अप्रभावकारी हो जाते हैं और वे विधियाँ ही प्रभावकारी रह जाती है जो मौलिक अधिकारा के विपरीत नहीं होती हैं। " संधीय संसद का सैनिका के लिए मौलिक अधिकारा को सीमित करन का अधिकार है। इसक अतिरिक्त यदि किसी क्षेत्र में सनिक कानून लागू है तो ससद विधि बनाकर उस क्षेत्र म मौलिक अधिकारी की सीमित कर सकती है।

समीका

सविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों की तीव्र आसोचना की गयी है। उसका सार अध्वत है

लय 'किस अधिकार से' है ? इस आदेश के द्वारा सर्वाच्च या उच्च यागालम किसी व्यक्ति वो रेसे पद पर काय करन में रोक सकता है जिसका वह अधिकारी नहीं है और किसी विरोध पद को रिक्त भी घोषित कर सकता है। इस समादेश नी जारी करन के सम्बाध मा 'याभावम को स्वविवकीय अधिकार प्राप्त हैं।

⁵⁷ रमेश थापर ननाम महास राज्य मे सर्वोच्च यायालय ने यही मत व्यक्त किया है।

⁵⁸ Ramesh Thappar vs State of Madras A I R 1950 S C 124 59 অনুষ্ঠার 32 (4)

⁶⁰ अनुच्छद 359

⁶¹ अर्नुच्छेद 358

(2) मीलिक अधिकारा पर निर्मारित विभिन्न प्रतिव था के कारण वे सारहोन हो गये हैं। निवारक निरोध व दौकरण एव सर्वेवानिक उपचारा को निलम्बित क रने सम्बन्धी उपवाधा पर विवेध रूप से आपित को जाती है। के अब अधिकारों के स्थिति होने पर तानाशाहों के उदय की सम्मावना को अस्थीकार नहीं किया जा सकता। मीलिक अधिकार एक हाथ सं दिये गये हैं और दूसरे से वापस ले लिये गये हैं।

(3) मौलिक अधिकार सम्बाधी मापा अस्पष्ट है। 'यह बताना कठिन है कि व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के अन्तमत क्या प्राप्त है।' एक आलोचक ने तो मौलिक अधिकारा सम्बाधी अध्याय का 'गौलिक अधिकारा पर प्रतिवाध' की सज्ञा दी है। आद्वयर अिनास के अनुसार, 'मारतीय मौलिक अधिकारा की मापा ठीक नहीं है। उसने अनेक चठिल बाते हैं और अमेरिकी अधिकार पत्र की माित वह स्पष्ट एव सिक्षित नहीं है।'

(4) सविधान य अधिकारों के साथ साथ क्तब्यों का उल्लेख नहीं है। उपरोक्त आदोचना वी समीक्षा वाछनीय है। इस के सविधान की माति मीलिक अधिकारों के आत्मात काम एवं अनिवास विश्वा आदि अधिकारों के शांतिम करने में स्थानार कि शांतिम करने में स्थानार कि शांतिम करने में स्थानार किया गया होता तो इससे राज्य के विचीय वायित्वों में अताधारण वृद्धि हो। वाती और इस आधिक नार को नवोदित स्वत न राज्य के लिए क्रेल पाना असम्मय था। इसके अतिरिक्त सविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्या के रूप मं इन अधिकारों को माति राज्य के मीति क्या विद्या गया है। अता के क्या इतना है कि मीलिक अधिकारों की माति राज्य के मीति निर्देशक तत्यों को क्या है। विचारक निर्देशक तत्यों की न्या या है। विचारक निर्देशक तत्यों की न्या या स्था के द्वारा रक्षा की ध्यवस्था नहीं की गयी है। विचारक निर्देशक तत्यों की नित्रिस्त करने की स्थाय पात्री नाति स्थाय प्रति का विकार के नित्र करने की स्थाय प्रति का स्थाय प्रति की स्थाय स्थाय स्थाय निर्देशक अधिकारों की नित्र स्थित करने की स्थाय प्रति का स्थाय स्थाय के स्थाय स्थाय की स्थाय के स्थाय स्थाय

⁶² श्री हरिविष्णु कामय ने मीलिक अधिकारा को निलम्बित करन की व्यवस्था की तीव आलोचना करते हुए कहा है कि इससे समग्रवादी राज्य—पुतिस राज्य— की स्थावना की जा रही है। सविधान समा ने जब इन प्रतिव या को स्थीकार किया था उससे समय भी कामव न यह कहा था कि 'यह दु से व हाम का दिन है। भारतीय जनता को ईस्वर मदद करे।'—Quoted by M V Pylce Indian Constitution, p 136

⁶³ Refer to British Emergency Powers Act 1920

⁶⁴ संयुक्त राज्य अमेरिका के भविषान के अनुसार अमेरिकी कांग्रेस को ब प्रियमिक प्रत्यक्षीकरण को निलम्बित करने का अविकार प्राप्त है।

35

स्थानीय शासन [LOCAL-SELF GOVERNMENT]

अधिकास अधिनित राज्य व्यापक क्षेत्रफल एव विद्याल जनसंख्या वाले द्या है एव प्राय सभी राज्यों के कायक्षण म वृद्धि हो गयी है । के द्रीय शासन के लिए पूरे देश जी व्यवस्था कर रकता समय नहीं है । जल सत्ता का विके द्रीकर शासन के लिए पूरे देश जी व्यवस्था कर रकता समय नहीं है । जल सत्ता का विके द्रीकरण, वित्ता हो के स्वाचित सत्त्याओं के समुचित कान के अमान में उनके हिता की उपका है । कि द्रीकरण का यह अथ है कि देश में विभिन्न सत्तरों पर सत्ता के के द्र स्पापित किय जाय । कि द्रीकर एक साम स्वाचित सत्ता हो । विके द्रीकरण का यह अथ है कि देश में विभिन्न स्तरों पर सत्ता के के द्र स्पापित किय जाय । कि त्रीकरण का महा स्वचित्र किया जाता है । विके द्रीकरण का यह अथ है कि देश में विभिन्न स्तरों पर सत्ता के के द्रायपित किया जाता वाहिए स्वाचित्र का स्वाचित्र का प्रशासन किया जाता को स्वचित्र स्वाचीय, त्राया स्वाचीय, त्राया स्वाचीय, यह स्वाचीय स्वच्या स्वाचीय स्वच्या स्वाचीय स्वच्या स्वाचीय स्वच्या स्वच्

स्पानीय शासन का एक अय प्रकार भी है। के द्वीय शासन द्वारा प्रशासन हेतु स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। यं अधिकारी के द्वीय विधियां को लागू करते हैं एवं के द्वीय शासन के एकेण्ट होते हैं तथा उसी के प्रति उत्तरदायों होते हैं। यह स्थानीय शासन का एक प्रकार होते हुए भी के द्वीय गासन का एक ही अग है। इसे भी हैरिस ने स्थानीय रायच शासन (Local State Government) सना दो है। यह उस स्थानीय शासन से मित्र हैं जिससे स्थानीय समस्याओं का प्रशा सन स्थानीय जनता की प्रतिनिधि सस्याशों द्वारा किया जाता है। ये स्थानीय निर्वाचित सस्याएँ—यथा, नियस, नगरपालिकाएँ, जिला बोड, काउच्टो, परिस, श्राम

पचायते आदि—राष्ट्रीय शासन के अधीन होते हुए भी अपने क्षेत्र मे उच्च सत्ता के निय त्रण से स्वतंत्र रहती हुई कुछ मामलों में निर्देशन एव दामित्व के अधिकारों से युक्त होती हैं। स्थानीय सस्याओं के अधिकार सीमित्त होते हैं। के द्वीय एव स्यानीय सासन की सवधानिक स्थिति एक दूसरे से सवधा मित्र होती है। के द्वीय शासन का आधार सविधान है। स्थानीय स्वशासन की सस्याओं की स्थापना के द्वीय शासन कर आधार सविधान है। स्थानीय स्वशासन की सस्याओं की स्थापना के द्वीय शासन या राज्य शासन की विधियों के अभीन होती है।

स्थानीय शासन का महत्व

स्थानीय शासन लोकत न की पाठकाला है। व्यक्ति के स्वत न विकास और सामाजिक नियानण, शानि एव विकास के मध्य समझीते का यह परिणाम है। काइनर के शब्दों में, "स्थानीय शासन स्थावर एवं समामुपातिक प्रतिमिक्ति की प्रतिया की श्रेणी में है और इनके द्वारा मीठ के अत्याचार से रक्षा का काय किया जाता है।" दी दाकविले के अनुसार, "नागरिकों की स्थानीय समाएँ राष्ट्र की शक्ति कहीं । विकास के लिए जो महत्व प्रारम्भिक पाठकालाओं का है वही महत्व नगर समाओं का स्वत नता के लिए हैं। किसी राष्ट्र द्वारा स्वत नता के लिए हैं। किसी राष्ट्र द्वारा स्वत न श्राक्षण की स्थानीय समापना की जा सकती है पर तु स्थानीय स्वशासन की सस्याओं के अमाय में स्वत त्रता की मायना नहीं आ सकती।" अपने स्वश्न मुल स्थानीय सासन की सस्याओं की आवश्यकता की निम्म तीन कारण मानता है

- (1) काव विभाजन के सिद्धात के अनुसार के दीय एव स्थानीय अधिकारिया के मध्य दायित्वा का विभाजन आवश्यक है।
- (2) समाज के निम्नतर स्तर की जनता की भी इन सस्याओं के द्वारा राज-गीतिक शिक्षा प्रदान की जाती है।
- (3) जनता के हितो एव कार्यों का प्रवाध उनसे सम्बाधित व्यक्तिया द्वारा हो मली प्रकार किया जा सकता है। स्पट है स्थानीय शासन अधिनायकतात्र के विकड़ रक्तापत्ति है एव अत्यधिक के द्वीकरण तथा के दीय शासन के अत्याधारा के विकड़ एक गारप्टी है। यह लोकतात्र की सफलता की आवस्यक पत है। इसस के दीय शासन के कायभार म कभी होती है। शासन के कार्यों से सम्बाधित होन क

¹ Local Government 'falls into the same category as such devices as federalism and proportional representation. They are safeguards against the tyranny of wholesale herd."—H Finer English Local Covernment, 1950, p. 4

^{2 &}quot;Local assemblies of citizens constitute the strength of free nations Town meeting are to liberty what primary schools are to Science. A nation may establish a system of free government but without the spirit of municipal institution, it cannot have the spirit of liberty." —De Tocquevelle. Democracy in America.

कारण जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है, स्थानीय समस्याओं का समा धान सीझदापुबक सम्मव होता है एवं सामा य नागरिका मे देश प्रेम, सहयोग, ईमानदारी, सच्चरितता, जात्मनिगरता आदि नागरिक गुणों का विकास होता है।

लेकिन स्थानीय शासन के उपरोक्त गुण वास्तविकता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं । स्थानीय स्वशासन की सस्थाएँ व्यवहार मे पक्षपात, भ्रष्टाचार, दलबादी एव स्थायपरता का अखाडा बन गयी है। इनसे स्थानीयता की भावना को प्रश्रय मिलता है। शासन की शक्तियों को के दीय एवं स्थानीयता के सच्य विमाजित कर देने के फलस्वरूप प्रशासनिक उत्तरदायित्व विमाजित हो जाता है। स्थानीय शासन लोक-तात्र की पाठकाला न रहकर वे लोकत त्र के स्वरूप को विकृत कर देते हैं। स्थानीय अधिकारियों में सत्ता के प्रति असाधारण लगाव होता है और स्थानीय अभावों के दवाव म आकर उनकी हुन्टि में स्थानीय हितों की तुलना में राष्ट्रीय हित गीण हो जाते है। सत्य तो यह है कि स्थानीय सस्याएँ स्थानीय हितो व स्थानीयता के गढ वन जाते है । मारत म स्थानीय सस्थाएँ एव उनका प्रशासन इसका प्रमाण है। नगर पालिकाओं म अण्डाचार एवं दलगत राजनीति के कारण उनके क्षेत्र में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इसका यह अथ नहीं है कि स्थानीय शासन की समाप्त कर दिया जाय। स्थानीयता एव विकेदीकरण के लिए हमे राष्ट्रीय हिता की उपेक्षा नहीं कर देनी चाहिए। इन दोषों के होते हुए भी स्थानीय शासन यदि ठीक प्रकार से सगठित हो एव सक्षमतापुर्वक काम करे तो वह राष्ट्रीय सुरक्षा, आधिक प्रगति एव सुदृढ लोकतातीय व्यवस्था का आधार बन सकता है।

स्थानीय स्वशासन के काय एवं स्रोत

सामा यत सभी देवों में स्थानीय संस्थाओं के काय निम्नवत् हूँ धिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, रोगों की रोक्याम, चिकित्सालया, बिलु गहों, सावजनिक स्वास्थ्य गहों आदि की व्यवस्था करना क्षेत्र को जनता के लिए यातायात एव आवागनर की मुविधा के लिए पुलिस, वस, ट्राम, मनोरजन, ग्रंत तमाशों और वाग-सगीचों आदि की व्यवस्था एवं प्रत थं, विजली, गस पानी, क्विंप की उन्नति का प्रव"प, लाध-पदावीं की देसप्राल, आदि ।

इत कार्यों को सम्पादित व रन के लिए स्थानीय सस्याओं को धन की आव स्थकता होती है। इनकी आय के प्रधान साधन गृहकर, जलकर, सीमाकर, व्यवसाय बर, साइविला, ठेला, यातायात कं अय बाहुना पर कर, मनोरजन कर, मना एव प्राथा के क्रय विकय आदि पर कर एव जासन स प्राप्त अनुदान आदि हैं।

विभिन्न देशों में स्थानीय शासन

प्रेट ब्रिटेन

. ग्रट जिटन की स्थानीय घासन की सस्थाएँ लोकत थ की मफल आधारशिलाएँ मानी जाती है। सही अर्थों म स्थानीय घासन लोकत त्रीय एव प्रतिनिधित्व प्रधान होता है। अंग के अनुसार, ब्रिटिश स्थानीय घासन के निम्न तीन मौतिक तत्व ह— (1) त्रिटिश स्थानीय घासन के निम्न तीन मौतिक तत्व ह— (1) त्रिटिश स्थानीय घासन अत्यात प्राचीन है। (2) यह समय एव परिस्थितियों के अनुसार विवर्तात होता रहा है। (3) यद्यपि स्थानीय सस्थाएँ अपनी रक्षा के लिए सतत प्रयत्नदिश रहती हैं पर सु उनकी श्रीविशा एव कार्यों म के द्रीम शासन द्वारा समान रूप से परिवतन किये जाते हैं। उड़ उड़ अवसन के अनुसार ब्रिटिश स्थानीय सासन साला स्थान का आपार विधि है न कि विश्वेषाधिकार। काई स्थानीय कमचारी विना वैध अधिकार के काय नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त विदिश स्थानीय शासन की सस्थाएँ अपने क्षेत्र में पूणत स्थतात एव स्थानस सम्पत्न होती हैं। सत्ता का प्रवाह उपर स नीचे की तरफ नहीं है अपितु प्रत्येक स्थानीय शासन की इकाई को यदि यह सद्मावपूवक काय करन का अधिकार है।

ग्रेट ग्रिटेन की स्थानीय स्वजासन की सम्याएँ लम्बे ऐतिहासिक विकास का परिणाम हैं। प्राय सभी देशों के स्थानीय शासन पर इनका प्रभाव पढ़ा है। अत इसे 'स्यानीय शासन की जननी' कहा जाता है। दीघ ऐतिहासिक विकास का परिणाम होते हुए भी ब्रिटेन में स्थानीय शासन का विकास पूर्व निर्धारित एवं नियोजित ढग स नहीं हुआ है। सैनसन राजाओं के काल से स्थानीय शासन की सस्थाएँ शाहर (Shire), हण्डे उस (Hundreds) एव वरा (Boroughs) थी । नॉमन विजय के पश्चात यह संस्थाएँ काउण्टी (County), मेनर (Manor) तथा नगरपालिकाएँ (Municipa lities) कही जाने लगी । इसी बीच मे परिश्न (Parish) एव टाउनशिप (Town ship) की स्यापना की गयी थी। एक हजार वर्षों से भी अधिक समय से यं सहयाएँ स्वायलता का उपभोग करती रही है। ट्यूडर एवं स्टअट वशीय राजाओं ने इसकी सत्तापर कभी प्रहार नहीं किया। 19वीं सदी के प्रारम्भ में इन विभिन्न स्थानीय सस्थाओं की सीमा एवं अधिकारो तथा क्षत्राधिकार के सम्बंध म जराजकता की स्थिति थी। एक समय तो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रो एव अधिकारों से युक्त 27 हजार स्थानीय सस्थाएँ थी। इनलैण्ड मे औद्योगिक काति के फलस्वरूप सामाजिक सरचना मे गम्मीर परिवतन आने लगे थे। नवीन नगरो का उदय होने लगा था। इनकी सफाई, शिक्षा एव स्वास्थ्य, नगर सुघार एव निघन सहायला की समस्याएँ उठ खडी हुई थी। एसद द्वारा नवीन सम्याओं की स्थापना की गयी थीं। पुरानी सस्थाएँ भी बनी रही। अत कायक्षेत्र एव अधिकारा के सम्बाध म विवाद उत्पन्न हो गये थे। 1835 ई म संसद ने म्युनिसिपल कॉपरिशन अधिनियम पारित किया । इसक द्वारा बरों के प्रशासन का पूनगठन किया गया । 1888 ई में स्थानीय ज्ञासन अधिनियम (Local Government Act) पारित करके काउण्टियो के प्रशासन का प्रनगठन

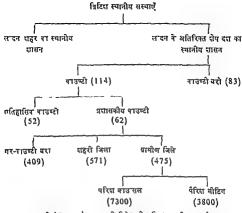
³ Ogg European Governments and Politics, 1939 pp 346 347

किया गया । 1893 ई ये ग्राम एव नगरीय जिला (Urban and Rural Districts) को व्यवस्थित करने के लिए एक व्या विधि ससद वे पारित की । 1929 ई के व्यिषितमम द्वारा कुछ जिलों को एक सुन ये वीष दिया गया एव स्थानीय संस्थाओं को व्याधिक सहायता देने की व्यवस्था को गयो । 1933 ई के स्थानीय शासन अधिनियम द्वारा स्थानीय अधिनयम द्वारा स्थानीय अधिनयम दिया गया । 1936 ई मे ट्रकमाय अधिनियम (Trunk Roads Act) एव 1946 ई के व्या सम्बन्धित अधिनियमों हारा राष्ट्रीय मार्गों को यातायात म नात्तय (Transport Ministry) के अधीन कर दिया गया तथा जनका व्यथ राष्ट्रीय कोय को दिये जाने की व्यवस्था को गयो । 1946 ई के एक व्याय अधिनियम द्वारा चिकत्सालयों की व्यवस्था को गयो । 1946 ई के एक व्याय अधिनियम हारा चिकत्सालयों की व्यवस्था को गयो । 1946 ई के एक व्याय अधिनियम हारा चिकत्सालयों के सीमाकन के लिए स्थानीय सासत सीमा आयोग अधिनयम की स्थापना की गयो । पर्यु इसे 1949 ई मे समाप्त कर दिया गया । 1944 ई म सबद ने एक विधि पारित करके निराक्षित खालकों के समुद्रित प्रवाय का सायित्व स्थानीय सस्थाओं को साप दिया । इसी प्रकार वृद्ध, अपगु, अप्ते एव बहुरे तथा गूगा को सर क्षण का वायित्व सत्वीय विश्व हारा स्थानीय शासन को सीप दिया गया है ।

ब्रिटिश स्यानीय सस्याएँ

त्रिटेन म भिन्न भिन्न स्थानो पर विभिन्न प्रकार की स्थानीय सस्थाएँ प्रचित्रत हैं। लग्दन सहर की अपनी वृषक सस्या है। शेप ब्रिटेन मे 1933 ई के स्थानीय सासन अधिनियम के अनुसार 6 प्रकार की स्थानीय सस्थाएँ स्थापित की गयी हैं (1) प्रशासकीय काउण्टी (Administrative County), (2) काउण्टी बरो (County Borough), (3) नान काउण्टी बरा (Non County Borough), (4) चहरी जिला (Urban District), (5) ग्रामीण जिला (Rural District), एवं (6) पैरिस (Parish)। कभी कभी एक ही क्षेत्र पर दो या तीन सस्थाओं का क्षेत्राधिकार हीता है।

स दन को छोड़कर सम्मूण देश काउण्टियो एव काउण्टी बरो में विमाजित है। काउण्टी स्थानीय स्वधासन की सबसे उच्च सस्या है। काउण्टी दो प्रकार की होती है प्रशासकीय काउण्टी एव ऐतिहासिक काउण्टी। वहे शहरो की स्थानीय सस्या काउण्टी बरो है। प्रशासकीय काउण्टी के अन्तगत गर-काउण्टी वरो (Non County Borough), शहरी बिले (Urban Districts) एवं ग्रामीण बिले होते हैं। ग्रामीण जिला म परिशो भी मो अपनी निजी परिपर्दे होती हैं। अब रेखाचित्र उपरोक्त सग उन का सप्ट करता है।



काउन्हों (County)—नाउन्हों ब्रिटेन की सदिया पुरानी सस्या है एवं स्था-गीय सासन की मर्वोच्च सस्या है । सम्यूच देस की 114 माया म विमाजित किया गया है। वाउन्हों से प्रकार की हैं प्रधासकीय एवं ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काउन्हिन्या गी सस्या 52 तथा प्रधासकीय काउन्हिन्या की 62 है। ऐतिहासिक वाउन्ही प्राचीन-वासी। अवर्धेय है एवं इनक कोई महत्वपूज काय नहीं हैं। ऐतिहासिक काउन्हिन्य गियाचित परिपर्व नहीं होती, कवल सीन प्रमुख अधिकारी होते हैं, लाड लेपटीनेट, प्रिक्त एवं परिस्त सांक पीस। लाड लेपटीनेच्च का पद बड़े सम्मान का होता है। उसी के द्वारा याय व्यक्तिया के नाय लिस्स सांक पीस के पदा के लिए प्रस्ताचित किय जाते हैं। वास्तव मं ऐतिहासिक काउन्हिन्यों पाधिक कोत्र है। इनका लाकसमा की सदस्यता के लिए निर्वाचन सीवा के रूप भ मी उपयोग किया हो?

प्रशासनीय कारुण्टिया नी स्थापना स्थानीय शासन अधितियम (1888 ई) ने अन्तगत की गयी है। के त्रीय शासन की नवीन प्रशासकीय कारुण्टियां स्थापित करने का अधिकार है। नारुष्टी परिषद शासन-काय करती है। इसा पूर्व अध्यक्ष, एल्डर-मत (Eldermen) एवं पार्थद या सहस्यम्थ होते हैं। पायदो (Councillors) को मतदाताओं द्वारा सीन वय के लिए निर्वाचित निया जाता है। पायदो की सस्या 1/6 एल्डरमैन होते हैं। एल्डरमैन का कार्यकाल 6 वप है, लेकिन बादे एल्डरमन प्रति तीसरे वप परचात अवकाश प्रहुण कर लेते हैं। परिपद का अध्यक्ष पापदो एव एल्डरमैना द्वारा सयुक्त रूप में एक वय के लिए चुना जाता है। अध्यक्ष को जिस्टस ऑफ पीस की मौति काय करने का अधिकार प्राप्त है। परिपद अध्यक्ष का वैतन निर्धारित करती है। परिपद की वप म कम से कम चार बठके होना आवश्यक है।

काउण्टी परिषद को पर्याप्त झक्ति एव दायित्व प्राप्त है। परिषद काउण्टी की देखमाल एव विभिन्न दायित्वों के सन्दम म नीति निर्धारित करती है। उसकी शक्तिया

एवं काय निम्नलिखित हैं

"काउण्टी का वजट बनाना, ऋण लेना, मकानो, सबका युको का सरक्षण, अनाषालया एव सुधार यहो की स्थापना, मानु महो एव क्षिश्च-कत्याण के द्रो, रिाका, स्वास्त्य, काउण्टी पुलिसके की व्ययस्या, साइसेन्स देना, सन्तमक रोगा की रोकपाम, काउण्टी के कमवारियो—कोषध्यक, स्वास्त्य अधिकारी, सर्वेक्षक—की व्यवस्या, क्षधीनस्य स्थानीय सस्याओ का निरोक्षण विस्कोटक पदार्थां, नापतील के बाटो, आदि के बारे मं नियम बनाना, आदि।"

काउण्टी के प्रशासन में परिषद की समितियों द्वारा महत्वपूण भूमिका अदा की जाती है। विधि के अनुसार प्रत्येक काउण्टी परिषद में 9 से 12 सक समितियाँ होती है, यथा—वित्त, शिक्षा, सावजनिक सहायता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गृह, कृषि, मात एवं शिदा-कल्याण आदि सम्बाधी समितियाँ।

काउण्टी की आय के मुख्य स्रोत गृह कर, भूमि-कर, सम्पत्ति कर है। इन्ह

के द्वीय शामन से विशेष कार्यों के लिए अनुदान प्राप्त होता है।

बरो (Borough)—वरो स तार्यय एसे खहरी क्षेत्रा से होता है जिन्ह 'नगर पालिका धासन पन' (चाटर) प्राप्त हो स्या हा 1 वरो तीन प्रकार के हाते है (1) सस्तीय बरो (Parliamentary Borough), (2) म्युनिसिपल बरो (3) काउणी बरो। सस्तीय बरो कॉम स समा के सदस्या के निवंचन की इकाई होते हैं। इनकी स्थानीय शासन स कीई सम्बंध नहीं होता। म्युनिसिपल बरो प्रशासकीय काउणी का है। एक माग होते हैं पर जु व ह पृथक रूप से शासन से 'आगणन' प्राप्त होता है। किसी म्युनिसिपल बरो की जनसस्था 75 हवार से अधिक हो बाने पर वह स्वास्थ्य म नास्य को काउण्टी बरो का दर्जा प्रदान करने के लिए आवेदन कर सकती है।

^{4 1948} ई के शिक्षा अधिनियम एव 1944 ई एव 1947 ई के नगर नियो जन अधिनियम डारा काउण्टी के शिक्षा, स्वास्थ्य एव नगर नियोजन सम्यापी कार्यों म पर्याप्त विद्व हुई है।

प्रत्यक काउण्टी म पुलिस व्यवस्था नही होती है ।

^{6 &}quot;A borough is simply an urban area that has received a charter" —Ogg and Zink op cit, p 367

सामा यत बरो की आबादी 1 लाख तक होती है, यदाप कुछ की जनसख्या 25000 तक है। बरो एव काउण्टी बरो में शक्तिया सम्ब वी ज तर होता है। प्रशासनिक ए भौगोसिक दृष्टि से बरो काउण्टी का माग होते हैं पर तु उनकी शक्तिया एवं अधि कार पृथक-मृथक होते हैं।

काउच्छी बरो-एक वडा परातु घना वसा हजा कस्वा, जिसके पास जपन क्षे से सम्बर्धित विभि न सेवाओं के सम्पादन के लिए पर्याप्त साधन होते है काउण्ट बरो बहलाता है। म्यनिसिपल बरो एवं काउण्टी बरो के काय एवं अधिकार समा होते है। बरो के अधिकार बरो परिषद (Borough Council) म किंद्रत होते है विधायी एवं कायपालिका कतव्या का बरो म प्रयक्करण नहीं होता। परिपद म एव मेयर, एल्डरमैन एव पापद (Councillor) होत हैं। मेयर को एक वप क लिए परियद निर्वाचित करती है । मेयर परिपद का अध्यक्ष होता है और विशेष अवसरो पर औपचारिक रूप सं वह बरो का प्रतिनिधित्व करता है । स्थानीय शासन के किसी विमाग का वह अध्यक्ष होता है । उसे अधिकारिया का नियस करते विमामो को नियानित करने और अध्यादेशा को अस्वीकार करने की पत्ति प्राप्त नहीं है। सामा यत भेयर पुनिविधित कर लिय जाते हैं। अधिकाशत उनक पट अवैतनिक हाता है। पापदों को प्रत्यक्ष रूप सं जनता प्रति तीन वय के लिए निर्वाचित करती है। एक तिहाई सदस्य प्रति वप अवकाश ग्रहण करत हैं। प्रति वप नवम्बर के महीने म नगरपालिका म निर्वाचन होते हैं। अधिकाशत य निर्वाचन दलीय आधार पर नहीं होते लेकिन जिन बरों में थम दल शक्तिशाली होता है उनमें बढ़ा सघप एव स्पर्धा होती है। एल्डर मना की सल्या कुल पापदा की एक तिहाई होती है तथा वे 6 वप के लिए निर्वाचित किय जात हैं। उनम स एक तिहाई प्रति दूसरे बप अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। बरो परिषद के काय-भार क अनुसार उसके साप्ता-हिक, पाक्षिक एव मासिक अधिवशन हात हैं। परिषद का अधिकाश काम समितिया द्वारा सम्पादित किया जाता है । मुख्य समितियाँ शिक्षा, वित्त, मात एव शिग-कत्याण, बद्धावस्था पेशन आदि सं सम्बन्धित होती हैं। अस्थायी समितिया की मी स्थापना की जाती है। बरो की शक्तिया का तीन मागा-विधायी, कायपालक एव वित्तीय-म वर्गीकत कर सकते हैं। उस उपनियम बनान का अधिकार होता है। इन नियमा ना स्वास्च्य एव कुछ अय सम्बाधित अधिकारिया द्वारा अस्वीवृत रिया जा सकता है। परिषद बरों के नोप नी सरक्षिका होती है। इस अनव प्रकार के नर लगान एव एकत्रित करने का अधिकार होता है। सम्पण नगरपालिका प्रशामन पर यह नियापण रसती है। वह अपने अधिकारिया जसे कि कोपाध्यक्ष, अभियन्ता (इजीनियर), मुस्य का स्टेबिल, स्वास्थ्य-अधिकारी आदि की नियक्ति करती है। परिषद की बठना म बरो के स्थायी कमचारियों को मान लेन का अधिकार हाता है परन्तु व मतदान

करते हैं तथा परिषद एवं कमचारीयण परस्पर पूण सहयो। अ नाय करते हैं

जिला (District)—दिटेन के स्थानीय शासन म दो प्रकार न---ग्रामीण (Rural) एव शहरी (Urban)---जिले होत हैं। इनकी स्थापना जिला एव परिश परिषद अधिनियम (1894 ईं) के अधीन की जाती हैं।

प्रामीण जिले—प्रामीण जिले कई परिया (Panshes) से मिल कर वनत हैं। इगलण्ड एव वस्त म इनको कुल सस्या 475 है। काउण्टी के द्वारा स्वास्थ्य, सफाई, प्रकाश आदि का प्रवाध समतापूवक न कर सकने के कारण काउण्टिया को जिला म विमाजित कर दिया गया है। ग्रामीण एव दाहरी जिले अपन क्षेत्रा म स्वास्थ्य, सफाई, एव प्रकाश आदि का प्रवाध करें हैं। इरोक ग्राम्य जिले में एक जिला परिपद होती है। 300 या अधिक व्यक्तिया की जनसंस्था वाला प्रत्यक परिस इस परिपद म अपन सहस्य भेजता है। सदस्यण्य सामायत तीन वप के लिए चुन जाते हैं। उनम एक तिहाई प्रतियत अवकाश प्रहण कर लेते हैं। जिला परिपदा म एक्टरमन नहीं होते हैं। परिपद अपना अध्यक्ष अपने सदस्या म से या वाहर ॥ निर्वाचित कर सकती है। प्राम परिपदों का समझ एक कावपदित काउण्डी परिपदा के पीसी होती है।

शहरी जिला— यहरी जिला की कुल सरवा 572 है। औद्योगिक विकास के फलस्वरूप जिस क्षेत्र की जनसंख्या अधिक हो जाती है उसे सन्वत्थित काउण्टी काउनल डारा शहरी जिला वना दिया जाता है। वरी एवं सहरी जिला नमार्थ्य स्काईमी है। वहे सहरी जिला को बरो का दवा विदाय जाता है। इस सन्वाभ कोई विस्क सीमा नहीं है। बरो एवं जिला गिर्या के सपठन म अंतर तो है पर तु शिक्त सोमा नहीं है। वेदो एवं जिला परिपद के सपठन म अंतर तो है पर तु शक्तिमों में कोई भेद नहीं है। किसी जनसमूह का पैरिश्व से ग्राम जिला एवं उससे आगे की विकास की अवस्था ग्रहरी जिला है। किसी ग्रहरी जिल की सस्या 20 हजार सं अधिक होने पर उसे प्रारमिक दिवा के नियं या सम्बाधी अधिकार प्रान्त हो जाते हैं। इससे दायित्व व कार्य वहीं हैं जो ग्राम्य जिले के हाते हैं। ग्राम्य जिलो के तर शहरी जिला की भी परिपद होती है। प्राप्य प्रकरी जिला को भी परिपद होती है। प्राप्य प्रकरी जिला को जो कार्य सम्यादित करने पटते हैं उनकी हरिट से वे वहत छोटे हात हैं।

परिष्त (Parsis)—ग्रामीण क्षेत्रों की सबसे छोटी इकाई परिछा होती है। 300 व्यक्तियों से अधिक जनसस्या बाले क्षेत्र य एक परिदा की स्थापना की जाती है। वैरिदा की एक परिपद होती है जिसमें 5 से 15 तक सदस्य होते हैं जो तीन वप के लिए निर्वाधित किये जाते है। इसकी प्रतिक्रिया व्यापक नहीं है। सडकों की सुरक्षा, जल प्रवाद, प्रकाश मनीरजन स्थलों का निर्माण, सानजनिक जावानात्त्र एवं सामाजनिक कार्याल्या स्वाद सके प्रपान कार्या समें परिपद के तीन या चार अधिवंदन होते हैं। 300 स कम जनसस्या वाले परिदा का प्रविद्या की एक समिति हारा किया जाता है।

क्ष दन शहर का प्रशासन (Government of London)—ल दन शहर का स्थानीय प्रशासन देश के श्रेप भाग सं पृथक है। 1855 ई एवं 1899 ई म. ससद ने ल'दन प्रदासन सम्बाधी पूचक अधिनियम पारित निये थे । स्वानीय शासन की हिन्द स ल'दन नगर को तीन मागा म विमाजित किया गया है—(1) ल'दा नगर (London City), (2) ल'दन काउण्टी (London County), एवं (3) ल'दन महानगरीय पुलिस जिला (London Metropolitan Polico District)।

- (1) स दन नगर का क्षेत्रफल केवल एक वममील है। पर तु सम्पूण ल दन नगर का क्षेत्रफल करीब 700 वगमील है। खदन शहर का श्वासन लॉड एक महापीर (मैयर) एवं निक्निलिनित तीन परियदों द्वारा होता है
- (अ) फोट आफ एत्डरमन (The Court of Eldermen)—यह नगर के बद्ध जना की समा है। इसकी सदस्य सख्या 26 है। महापौर इसका जब्यक्ष होता है। इसके सदस्य जीवन मर के लिए निर्वाचित होते हैं। इस परिपद का काय दलालों की लाइ से स प्रदान करना और नगर के अमिलेखों को सुरक्षित रखना है।
- (व) कोट आफ कॉमन कॉव सस (The Court of Common Council)—
 यह नगर की वास्तविक प्रशासकीय सस्या है। इसने कोट ऑफ एल्डरमन के 26 सदस्य
 एव 206 अब पायद (बांड सतर) होते हैं जो प्रति वय चून जाते हैं। इसका काम
 पुतिस, सिविल एव अपराधिक वायालयों का निरीक्षण, आवश्यक उपनियमा का
 निर्माण एव पुता का निरीक्षण करना होता है। परिपद समितियों के माध्यम स
 वाय करती है।
- (स) कोट ऑफ कॉमन हाल (The Court of Common Hall)—इसम कोट ऑफ एड़दमन के सहस्य एव नघर की कम्मिनयों के लिबरीमन (Liverymen) हीते हैं। यह एक प्रकार की नगर समा है। लाड मेयर का निर्वाचन केट आफ कॉमन हाल के दारा उन वरिष्ठ एड़दरमेंनों में से होता है जो वैरिफ रन् चुकत हैं। लाड मेयर के दारा कोई महत्वपूण काम नहीं किया जाता है। यह तीना परिपदा की अध्यक्षता करता है एवं विषेप अवसरों पर ल'दन शहर का प्रतिनिधित्य करता है। उसका अधिकाश वेतन शासकीय समारोहों म ही ज्यद हो जाता है। अत यह पद केवल धनी व्यक्तियों के लिए ही उपयुक्त है। लांड मेयर के पद को आतोचना भी की जाती है तथा इस उच्च पद को समाप्त करने की मौंग की गयी है ताकि ख'दम काउच्छी के समापति को ल यन की राजनीत में उपयुक्त स्थान प्राप्त हो सके।
- (2) ल दम काउण्टी —यह प्रशासनीय काउण्टी है। 1855 ई क काउण्टी परिपद अधिनयम के अधीन ल दन म एक काउण्टी परिपद की स्थापना की गयी है। इसम 28 वरो हैं। इनम प्रत्यक में अपनी परिपद है जिनका समठन एव शक्तियाँ का प्रशासन की निर्माण के प्रशासन की लाउण्टी परिपद के मिल्यों के साव की समजन एवं शक्तियाँ में 124 निर्वाचित सदस्य एवं 20 नयरबुद (एल्डरमैन) है। पायदों को जनता हारा तीन यप एव नयरबदों को 9 वप के लिए निर्वाचित किया जाता है। एक-तिहाई नयरबुद प्रति तीन वप परचात अवकाय ग्रहण कर सेते हैं। पायद एवं नयर

वदो द्वारा सम्मिलित रूप से परिषद के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। इस परि-पद की अध्यक्षता के अतिरिक्त अय कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। परिपद का मूख्य नाय सावजनिक स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा, सडके, रेलवे पाक, मनोरजन-स्थला आदि ना प्रवाध करता है। नाटयगहा की लाइसेन्स देना, गहा भी व्यवस्था एव निरीक्षण, मकाना सम्ब धी नियमो एव अनाथालया की व्यवस्था भी परिपद के दायित्व हैं। नाउण्टी परिषद की आप के मुख्य स्रोत-किराया, शुल्क, लाइसे स शुल्क, स्थानीय चुगी एव सीमा करा स प्राप्त आय एव शासकीय अनुदान है । परिपद को ससद की स्वीकृति से ऋण लेने का भी अधिकार है। इसका अपना पृथक वार्षिक अजट होता है। परियद का अधिकाश काय समितिया द्वारा सम्पादित किया जाता है।

(3) ल दन महानगरीय पुलिस जिला-ल दन नगर क चारो ओर महानगरी का पुलिस जिला है जिसका क्षेत्रफल लगमग 700 बगमील है। 1829 ई मे सर रॉबट पील ने महानगरी पुलिस जिला की स्थापना की थी। पुलिस आयुक्त इसका प्रधान होता है जो फाउन द्वारा नियुक्त किया जाता है। पुलिस आयुक्त का पद राज-मीतिक पद नहीं है अपित दीघ प्रशासकीय अनुभव का व्यक्ति ही इस पद पर नियुक्त किया जाता है। इसकी सहायता के लिए तीन सहायक आयुक्त होत हैं। बिटिश स्थानीय शासन पर के ह का नियायण

एक सदी पूर्व स्थानीय सस्याओ पर के द्रीय दासन का बहुत कम नियंत्रण था। स्थानीय सस्थाए उस समय अपने क्षेत्र म पर्याप्त स्वायत्त सम्पत्न थी पर तु आज स्थिति भित्र है। अब के द्रीय शासन का नियानण स्थानीय सस्थाओं पर बढ गया है और इसमे दिन प्रतिदिन बद्धि होती जा रही है। के द्रीय नियानण म बद्धि का कारण यह है कि स्थानीय सस्थाएँ ठीक एव नियतित दग से अपने दायित्वा को सम्पादित नहीं करती है। प्रश्न यह है कि क्या स्थानीय सस्थाओं को अनियानित उप से काय करने दिया जाय ? इस स दम मे सामा य धारणा यह है कि जहा स्थानीय सस्याए पिछडी हुई हैं वहाँ के द्रीय शासन को उन्ह प्रोत्साहित करना चाहिए और जहाँ वे अपनी शक्ति का दरुपयाग करती हैं वहाँ के द्रीय शासन को उन्ह रोकना चाहिए। स्थानीय शासन के सुघार की माग वढती गयी। फलत ससद द्वारा विधि पारित की गयी जिसके फलस्वरूप पुरानी सस्याओं को समाप्त करने नवीन सस्याओं का निर्माण किया गया और उन्हें ज य शक्तियाँ तथा कर लगाने के अधिकार प्रदान किय गये।

स्थानीय शासन पर कडीय निय त्रण के निम्न तीन रूप हैं

 विधायी नियात्रण--िप्रटिश ससद सम्प्रमु है । उस स्थानीय शासन के सम्बाध म सब प्रकार के विधि निर्माण उनके अधिकारी की व्याख्या तथा नवीन शक्तियाँ एव अधिकार भेत्र प्रदान करने, प्राचीन संस्थाओं के स्थान पर नवीन संस्थाओं के निर्माण आदि का अधिकार प्राप्त है। ससदीय विधि द्वारा प्रदत्त यक्तिया का ही प्रयोग इन सस्याओं ने द्वारा किया जा सकता है।



लसा परीक्षण ने त्रीय सम्मान्यरोक्षका (Auditors) ना दायित्व होता है। अनुचित व्याम ने रोकने का इ हु अधिकार होता है तथा स्थानीय धाखा के राजस्व म जिन अधिकारिया के प्रमाद स होति होती है उह सर्वाज देन ने लिए बाध्य वर सकत है। हमरणीय है कि बरो के वित्तीय प्रवासन म ब्रिट्मीय अनुदान सन्वर्षी व्याप का लेखा परीक्षण है कि बरो के वित्तीय प्रवासन म ब्रिट्मीय अनुदान सन्वर्षी व्याप का लेखा परीक्षण के द्वीय विद्यास विधा नियम एव 1945 इ के जलीय अधिनियम द्वारा स्थानीय चासन को सम्बध्ति मामसे म हस्तक्षेय ने च्यायक अधिकार प्रमाद हो गय हैं। नियाखित रीति के त्रियाखयन के लिए सम्बध्ति मानिया वा स्थानीय सस्याआ को निर्देश देने एव पहल करने के अधिकार प्राप्त होते हैं। देने एवं एहल करने के अधिकार प्राप्त होते हैं। वे दे एवं (Capital expenditure) के बार म सम्बध्ति सन्तर्भी री स्थाहत लेना बायस्यण होता है।

(3) याविक नियानण—स्यानीय सस्याएँ एव अधिकारिया द्वारा केवल उन्हीं यक्तिया का प्रयोग किया जा सकता है जो उन्ह मूल ससदीय विधिया तथा परवर्ती विधिया द्वारा प्रदान की गयी हैं। यदि कोई स्थानीय मस्या या अधिवारी अविरिक्त विधिया द्वारा प्रदान की गयी हैं। यदि कोई स्थानीय मस्या या अधिवारी अविरिक्त विधिया द्वारा प्रदान की गयानिय को आवदन किये जाने पर ऐस कार्यों को अवैधानिक एव निष्प्रमानी पाणित करन का अधिकार प्राप्त है। दमी प्रकार स्थानीय सस्याओ द्वारा निर्मित उपनियम यदि मूल सबदीय विधि के विपरीत होत हैं या वे उसका अविक्रमण करते हैं तो न्यायालय उन्हें निष्प्रमावी योधित कर सकता है। स्मरणीय है त्रिटिल न्यायाधीया ना उपनियमा के प्रति उदार इस्टिकोण होता है। इसके अविरिक्त स्थानीय सस्याना के कुछ अनिवाय दायित्व होते हैं। इन दायित्वा को सम्यादित करन म स्थानीय सासन यदि असकत होता है तो यायपालिका की धरण ती जा सकती है। यायालय स्थानीय द्यासन के कतव्य सम्यादन के लिए परमादेश का आदेश (Writ of Mandamus) जारी कर सकता है। परन्तु न्यायिक नियत्रण की ध्यक्षया खर्चीली एव विवानकारी होती है।

समीका—ग्रेट त्रिटेन स्थानीय संस्थाओं का युह है। आज भी त्रिटिश स्थानीय संस्थाओं को पर्याप्त स्वतं त्रता त्राप्त है। के द्रीय धासन का नियत्त्रण यद्यपि बढता जा रहा है फिर भी नियत्त्रण काफी सचीता है। उसका उद्देश्य स्थानीय शासन के कार्यों म सुधार करना होता है। स्थानीय सस्पाएँ ही अपने कमचारिया एवं अधि कारिया की निपुक्ति करती हैं, आय व्यय का वार्षिक विवरण (बजट) तैयार करती है, सम्बचित सामन के प्रसासन करती है तथा उपनियम बनाती हैं। के द्रीय एवं स्थानीय शासन के पारसारिक सम्बच्ध उच्च एवं अधीनस्थ निकायों के नहीं हैं अपितु माफीडारों (Partners) जैसे हैं।

स्थानीय सासन म सुपार के लिए समय समय पर सुभाव दिये गये हैं। ब्रिटिय ससद ने 1945 ई म स्थानीय ज्ञासन सीमा आयोग अधिनियम पारित किया था। इम अभिनियम द्वारा स्थानीय सीमा आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गयी थी। स्यापित आयोग ना मत या नि नाउण्टिया एवं वरा की सीमाओं म आशिक संशोधन जयवा एक या दो काउण्टिया एवं बरो के विभाजन या एकीकरण संसमस्या का समाधान नहीं हो मरता है। अत आयोग न यह सुनाव दिया कि ससदाय विधि द्वारा नवीन प्रकार की स्थानीय इकाइया का निमाण किया जाना चाहिए और उनक दायित्वा एवं गत्रध्या को पून निषारित किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त वतमान सस्याओ क स्थान पर काउण्टी काउण्टी करो एव काउण्टी जिला की स्थापना का गुभाव दिया सया एक्स काउपनी एवं दि वाउपनी पदित का प्रस्ताव किया या । आयान की सिफा-रिशा का मिथित स्थागत हुआ अधात तीत्र आवीचना व साथ-साथ समधन भी हुआ पा। स्वास्य्य म त्री ए पूरिन विवान (Anurin Bevan) न भी आयाग की सिपा-रिवा को पसन्द नहीं किया। पखत 1949 ई म 1945 ई का अधिनियम रिरस्त कर दिया गया समा आयाग का विषटित वर दिया गया। 1958 ई म ससद व स्यानीय शासन अधिनियम व अधीन इंगलण्ड एवं वस्स ने लिए प्रयव सीमा आयाग की स्थापना की गयी है। इन आयोगों के स्थानीय झासन वे पूनरीक्षण एवं नवीन प्रकार की सस्याओं की स्थापना सम्बाधी सुनावा का अधिकार दिया गया है। 1966 ई के द्वासन व स्थानीय द्वासन की विसीय स्थिति सम्बन्धी खेत पत्र म यह स्वीकार किया गया है कि स्थानीय शासन के कराधान की यतमान पद्धति दाप-पूर्ण है। ब्रिटिश स्थानीय शासन म सुधार की आवश्यकता का अधिक अनुसब नहीं शियाजारहा है।

फाल से स्थानीय जासन

कास की स्पानीय प्रासन-व्यवस्था अपन दग की अनुठी है। सम्यूप फास 90 डिपाटमण्टा (Departments) म विमाजित है। डिपाटमण्टा कैण्टना म, कण्टन अनेक अरेडाईजमण्टा (Arrondissements) म विमाजित हैं। स्वस छोटी इकाई कम्यून है। अनेक कम्यून अरडाईजमण्टा म सगठित होते हैं। अत फास म डिपाटमण्ट, कैण्टन, अरेडाईजमण्ट एव कम्यून स्थानीय ग्रासन की इकाइयों हैं। एक कैण्टन म

सामा यत 35 कम्यून होते हैं।

हिपाटमेण्ट (Department)—कास में कुल 90 हिपाटमेण्ट (या हिपाटमा) हैं। डिपाटमेण्ट फास की सबसे बड़ी प्रसासनिक इकाई हैं। एक डिपाटमेण्ट का सामान्य क्षेत्रफत 2363 वर्गमील हाता है। सीन (Senne) का हिपाटमण्ट सबसे छोटा है। उसका संत्रफल 185 वर्गमील एव सबस वह डिपाटमेण्ट वोरहेबस (Bordeaux) का क्षेत्रफल 4140 वर्गमील है। सभी दिपाटमण्टा को 4 समूहा में विमाणित किया जाता है (1) होर्स (Horz) वग के डिपाटमण्ट जिनकी सस्या 15 है। इनमें फास के प्रमुख नगर स्थित है। (2) प्रथम खेणी के 19 डिपाटमेण्ट जिनके अत्यस्त प्रातीय राज-सानिया आती हैं। (3) दितीय प्रेणी के 22 छोटे डिपाटमेण्ट, एव (4) तृतीय श्रेणी के 34 डिपाटमण्ट।

प्रत्येक डिपाटमेण्ट म एक सामा य परिषद होती है। इसके अतिरिक्त प्रोफेक्ट (Prefect) डिपाटमेण्ट का कायपालिका प्रमुख होता है।

डिपाटमेण्ड की सामा य परिषद—डिपाटमण्ड की सामा य परिपद एक शक्ति साली अग है। इस परिषद ने लिए प्रत्येक नण्डन द्वारा एन पापद (Councillor) नुना जाता है। डिपाटमण्डो के आकार एव क्षेत्र के अनुसार उनकी परिपदा की सदस्य-सस्या म अग्तर होता है। प्रत्येक पापद 6 वप के लिए निर्वाधित किया जाता है, परंजु एक-तिहाई सदस्य प्रति शीन वप परंचात अववाध सहज कर लेते हैं। मता-किकार ने लिए डिपाटमेण्ड से सम्पत्ति या आवास सम्बन्ध यो योग्यता आवश्यक होती है। चौषाई पापदा के लिए डिपाटमेण्ड का निवाधी होना आवश्यक नहीं हाता है। सामा परिपद राष्ट्रीय अवेग्यली की स्वीकृति से झासन को विपटित कर सनती है। सामा परिपद राष्ट्रीय अवेग्यली की स्वीकृति से झासन को विपटित कर सनती है। ऐसी स्थिति मे नवीन निर्वाचन तुर त हो होने चाहिए। परंजु 1874 ई से किसी भी सामा प परिपद को विपटित नहीं किया क्या है। येर कानूनी काय के लिए अपने पापद को सामा परिपद स्वय परच्युत कर सकती है। सामा य परिपद के वप में से सामा प अधिवेशन होते हैं। प्रोक्टर को दो तिहाई पापदो की प्राथमा पर विपेष सधिवेशन आहूत करने का अधिकार हो। सामा परिपद अवन अध्यक्ष को एक यप के लिए निर्वाचित करती है। वह पुन निर्वाचित हो सकता है।

परिषद को व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। उसे डिपाटमेण्ट के अतिरिक्त कम्यूना के शासन से सम्बन्धित शक्तियाँ भी प्राप्त है। राज्य प्रशासन की इमारतो की सुरका, राज्य सेवाओ का सगठन, शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति शिक्षा का प्रशिक्षण, दीवानी, अपराधिक एव व्यापारिक तथा भ्रमणज्ञील यायालयो की व्यवस्था करना सामाय परिपद का ही दायित्व है । डिपाटमेण्ट द्वारा सचालित विभिन्न सेवाओं का सचालन तथा राजकीय मामलो का प्रशासन भी सामा य परिषद के कायक्षेत्र मे आते हैं। परिपद की सिफारिश पर ही राज्य द्वारा डिपाटमेण्ट के अ तगत चन्न, कृपि सस्याओ, प्रायमिक पाठवालाओ आदि के लिए अनुदान प्रदान किये जात है। आर्थिक नीति एव सामाय प्रशासन के सम्बाध में परिषद का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार है। कम्यूनो की कुछ सेवाआ पर सामाय परिषद को नियात्रण प्राप्त है। जनता को दी जाने वाली सहायता के सन्दम म परिषद को व्यापक अधिकार हैं। कम्यूना म उत्पन विवादों का भी फसला वही करती है। वह डिपाटमेण्ट सं सम्बन्ति सभी नीतियों को निश्चित करती है। वित्तीय व्यवस्था पर उसका पूण निय त्रण है, लेकिन सामा व परिषद द्वारा पारित वजट को गृह मानी स्वीकृत करता है । सामा व परिषदों के निण्या को विधिक औचित्य की ट्रप्टि से काउन्सल आफ स्टेट के समक्ष चनौती देने का अधिकार प्रीफेक्ट को प्राप्त है।

सामा परिषद की एक स्थायी समिति होती है जिसे डिपाटमेण्ट का आयोग (Commission Departmentale) की सना दी जाती है। इसका मुख्य काय प्रीफेक्ट के हिसाव किताब की जाच करना होता है। आयोग इसके अतिरिक्त अनक उपयोगी काय भी करता है। इससे सामा व परिपद की वट्टत बचत होती है।

प्रोफेक्ट iPrefect)—विपाटमेण्ट का कायकारी अध्यक्ष प्रीफेक्ट कहलाता है। इसकी नियुक्ति गहम श्री की सिफारिश पर फेक राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति ही उसे परच्छुत करता है। सामायत शासन जब किसी प्रीफेक्ट की परच्छुत करता है। सामायत शासन जब किसी प्रीफेक्ट की परच्छुत करता है। तो अप पर पर एर हस्तातरिक्त कर दिया जाता है। उसे क्यापक अधिकार प्राप्त हैं। व्यवस्था एव शासि स्थापित करता, सुरक्षा, अपने क्षेत्र म विधिया का कियाचित करता उसका ही दायित्व है। वह अपने क्षेत्र में पुलिन विमाण का अध्यक्ष होता है। अपराधिया को ब दी बनाने एव तसाशी क्षेत्र के व्यापक अधि कार उस प्राप्त है। वह विपाटमण्ट के अतगत राज्य की संमस्त प्रशासनिक एव प्राविधिक सेवाजा में सम बय स्वापित करता है। राज्य कोप से धन उसी के अधिकार स दिया जा सकता है। वह निम्न अधिकारियों की नियुक्ति करता है। के दे हो तो हो। वह अपने क्षेत्र की सामाय परिपद का कावकारी अधिकारी होता है। कमी-कभी वह विमान विमाणों के अधिकारियों के बार म भी निश्चय करता है। कमी-कभी वह विमान विमाणों के अधिकारियों के बार म भी निश्चय करता है।

प्रीफेनट को दोहरी भूमिका निमानी पडती है। उसकी डैंड स्थिति है। एक तरफ वह डिपाटमेण्ट का प्रमुख नायनारी अधिकारी होता है तो दूधरी तरफ वह के द्रीय सासन का अभिकर्ता है। के द्रीय खासन के अभिकर्ता के रूप य वह के द्रीय विधिया एवं आदेशा को कियानित करता है। शासन के विभिन्न विभागी (पया—राजमार, पुल, जेल, जनायालय एवं चिकस्तालय) का अध्यक्ष होता है। वह सेना म मर्ती के प्रव प का निरीक्षण करता है। अनेक अधिकारियों की नियुक्त करता है। वह सिक्य राजनीतिन भी होता है। सामा य निर्वाचन म वह अपने समयक मित्रया के पक्ष म सिन्य रहता है। शिष्टाटमेण्ट ने अध्यक्ष के रूप म वह सामा य परिपद के सभी काय सम्यावत करता है। शोफेक्ट के इन दोना वायित्वा म समयं करना कठिन काय है। इस फेक्ट प्रीफेक्ट एवं उसके अधीन कमचारी सम्भण देश के प्रवासन की वार्ति है। शोफेक्ट के इन दोना वायित्वा म समयं वर्ति है। शोफेक्ट के इन दोना वायित्वा म समयं वर्ति है। शोफेक्ट के इन दोना वायित्वा म समयं वर्ति है। शोफेक्ट के इन दोना वायित्वा म समयं वर्ति हैं पर तु प्रीफेक्ट एवं उसके अधीन कमचारी सम्भण देश के प्रवासन की गतिमान रखते हैं। पर तु प्रीफेक्ट एवं उसके अधीन कमचारी सम्भण देश के प्रवासन की गतिमान रखते हैं।

कप्टन (Canton)—प्रशासनिक कार्यों की हृष्टि से कुछ कम्यूना को कैण्टना म गठित किया जाता है। फास में कण्टन सेना और न्यायपासिका की मुख्य प्रशास निक इकाई है। कण्टन ही डिपाटमेण्ट के स्थानीय निवाचना को इकाइयी होती हैं।

अरे डाइजमेण्ड (Arrondissement)—यह मुख्य प्रशासकीय उपकेष है। इसकी कोई निवाचित परिषद नही होती है। एक डिपाटमेण्ड म तीन या चार जरेंडाइजमेण्ड होते है। इनका अध्यक्ष उप प्रीफेक्ट कहनाता है। प्रत्येक अरे डाइजमेण्ड एक लघु डिपाटमेण्ड के समान है। उप प्रीफेक्ट प्रोफेक्ट का अमिकर्ता मान होता है। वह मित्रमण्डल की उँगलियाँ ही नहीं अपितु और व कान मी होता है। यह कम्यून कं अध्यक्षा तथा मेयरो का परामश्रदाता, मागदश्वक एव प्राविधिक सलाहकार होता है। अरे डाइजमेण्टो म पहले परिपदे हुआ करती थी। अब उनव काय प्रीफेस्टा को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं। आये के अनुसार, कास के स्थानीय सासन में अब इनका वह महत्त्व नहीं है जो इ'ह पहले प्राप्त था, अब यह केवल विधानमण्डल के सदस्यों के निर्वाचन सेश के के एक स्थानीय सासन में अब इनका विधानमण्डल के सदस्यों के निर्वाचन सेश के रूप में रह मधे हैं।

कम्यून (Communes)—फास म कम्यून से अप नगर, राहर (Town), कस्वा या ग्राम से होता है। फास मे चाहरी एव ग्राम्य स्थानीय द्यासन मे कोई अतर नहीं है। फास मे करीव 38 हजार कम्यून हैं। प्रत्येक कम्यून म एक नगरपालिका परिपद (Municipal Council) एव एक नेयर होता है। जनसस्या के जाधार पर परिपद की सदस्य सक्या निक्चित की जाती है। वेयर कम्यून का कायकारी अधिकारी होता है। हिपाटमेण्ट के प्रीफेनटो की मांति उसकी हैंथ स्थिति है। एक तरफ वह परिपद का कायकारी अध्यक्ष होता है तो दूसरी तरफ अपने उच्च अधिकारियों का अभिकतरों होता है। डेच व्यापक अधिकार एव शक्तिया ग्राप्त होती हैं। इनके प्रयोग के सम्ब प्र म उसे व्यापक अधिकार एवं शिष्टा ग्राप्त होती हैं। इनके प्रयोग के सम्ब प्र म उसे व्यापक स्विविवेशीय अधिकार मी ग्राप्त हैं।

पैरिस की अपनी पृथक शासन व्यवस्था है। अपनी पृथक नगर परियद है। फास म स्थानीय सस्थाओं के राजस्व के तीन मुस्य स्नोत है चुगी, सम्पत्तिकर एवं स्थानीय कर। इसके अतिरिक्त के द्रीय शासन द्वारा स्थानीय सस्याओं को आर्थिक अनुवान दिया जाता है।

फास में स्थानीय शासन एवं के डीय शासन के सम्बंध

कास म स्थानीय धासन पर के द्वीय धासन एव उच्च अधिकारियों के नियंत्रण की विधिवत व्यवस्था की गयी है। कंद्रीय नियंत्रण या सरक्षण दो प्रकार का है (1) राजनीतिक एव (2) वित्तीय। राजनीतिक सरकाण के बत्यत स्थानीय धासन के अधिकारिया को गद्य व्यवस्था की प्राप्त होती है। प्रभिकेट नेयर को एक माह एव गृह-मानी तीन माह के लिए वितिस्वत कर सकता है। गम्मीर अपराधों के लिए गृह-मानी उसे पदच्युत भी कर सकता है। अनेक बार मेयरों को इसिए एदच्युत किया गया था कि उन्होंने विधि के अद्रु सार या सुवासन एव व्यवस्थित रीति की हिष्ट से ठीक प्रकार काय नहीं किया है। नगर परिपदों की सामाय परिपदों की मी प्रधासनीय बादेश द्वारा समायन किया जा सकता है।

के दीय शासन निम्न तरीका संस्थानीय शासन पर नियायण रखता है

(1) के द्वीय शासन स्थानीय निषया की वैधानिकता सम्ब धी परीक्षण करता है। कुछ निषया के सम्ब घ म स्थानीय निकाया को प्रीफेक्ट, म त्री एव राज्यपरिपद (Council of State) की स्वीकृति सेना आवश्यक होता है।

- (2) अनेक मामलो में स्थानीय इकाइयों को निणय करने के अधिकार उस समय तक प्राप्त नहीं होते जब तक कि सरक्षक सत्ता द्वारा तत्सम्बाधी अधिकार प्रदान न कर दिये आयें।
- (3) स्थानीय शासन के वित्त पर उच्चाधिकारियो एव मन्त्रिया का नियात्रण होता है। नगर परिपदो के बजट को उप प्रीफेतटा तथा कम्यूनो के बजट को प्रीफेस्टा द्वारा स्थीकृत किया जाता है। वडे कम्यूना के बजट को ग्रह मन्त्री स्थीकृत करता है। विपाटमण्ट का बजट यह मन्त्री एव वित्त मन्त्री हारा स्थीकृत किया जाता है। कम्यूनो को न्त्रण तैन एव अपनी सम्पत्ति को 18 वप से अधिक समय के लिए पटटे पर उठाने के लिए विश्वय अनुमति लेना आवश्यक होता है।

के द्वीय शासन का बित्तीय सरक्षण ने अधीन स्थानीय सस्याओं के वजट को स्वीकृत करने एवं लेखा परीक्षण (auditing) के अधिकार प्राप्त है। निकट भूत में ही के द्रीकरण एवं के द्रीय सरक्षण की इस प्रवृत्ति का विकास हुआ है। प्रीफेक्टो को कुछ शक्तिया से विचत करने के अधिकार मित्रया को प्रदान किये गये हैं। एक नवीन अधिकारी Tresorier Bayeur General की नियुक्ति की गयी है। इसे सरक्षण सम्बाधी स्थापक अधिकार प्राप्त है। स्थानीय सासन के कमचारिया एवं अधिकारया का द्रीपस्य अविकारी गहु म नी होता है। अत फेच स्थानीय सासन की सबसे महत्वपूण विशेषता 'सरक्षण मिश्रित के द्रीकरण है।

सयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानीय शासन

संयुक्त राज्य अमेरिका म 91 हजार से भी अधिक स्थानीय सस्थाए है। विधि-धता यहा के स्थानीय घासन की एक प्रमुख विद्येषता है। कोलिम्बया जिला सिहत लगभग 48 प्रकार के स्थानीय घासन है। इसकी प्रमुख इकाइयाँ है काउण्डी (County) राजन (Town), टाउनशिय (Township), एवं नवर (Cities)।

कांउण्टी—स्थानीय घासन की सबसे बडी इकाई कांउण्टी है। लासियाना (Louisiana) राज्य को छोड़कर वाकी सभी राज्य कांउण्टिया म विमाजित हैं। सभी राज्य म इनकी कुल सख्या 3049 है। दिलावरा राज्य म कवल तीन कांउण्टियों है जब कि टक्सास म 250 हैं। सामा यत प्रत्यक राज्य म 50 स 100 तक कांउण्टियों होती है। कांज्यों सम्बन्धित कार्यों के लिए राज्य की प्रधासनिक इकाई होती है। राज्यों के सिंघान द्वारा इंह विधिक मा यता प्रत्य को ताती है। कांज्यों का प्राच्यों के सिंघान द्वारा इंह विधिक मा यता प्रचा की जाती है। कांज्यों का प्रधासन एक परिपद (Council) या लायुक्त या बोड़ करता है। परिपद क सदस्य निर्वाचित होते हैं। रामान्यत इन परिपदा म 3 से 7 सदस्य होत है। परन्त इस्त

^{7 &#}x27;The authority in a country is centered in a group of elected officials known as a 'Gouncil, Commissioners or Board' (p 334), or supervisors elected by the voters (p 295) —H Zink and others American Government and Politics, 1967

काउण्टियों की सदस्य सम्या अधिक होती है। सिमित या परिपद के अतिरिक्त काउण्टों में शैरिफ (Sheriff), लिपिक (Clerk), सरकारी (अभियोग) बकील (Prose cutor Attorney) एवं कारोनर (Coroner) आदि कुछ प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। यह सभी निर्वाधिक होते हैं। काउण्टियों में सामायत मेयर (Mayor) या स्पीकर या उपराज्यपाल (Lieutenant Governer) नहीं होते। यदाप कुछ बोडी के अध्यक्ष (Chairman) जनता द्वारा निर्वधिक होते हैं और नाममान की मूमिका निर्माद है। वैदिश्ली राज्यों में काउण्टी के कुछ अधिकारी—जसे यायाधीश, काउण्टी किपिक लादि—परिषद के सदस्य होते हैं। काउण्टी परिषदा में समितिया की मूमिका नाममान की है।

काउण्टी के प्रमुख कायें निम्नवत् हैं व्यवस्या एव शांति की स्यापना, सम्य यित कागजातों का सरक्षण, रयानीय विद्यालयों का निरीक्षण, परिमट एवं लाइसे स देना, जेल, प्रामीण क्षेत्रा, सडको एव अप कल्याणकारी कार्यों का निर्देशन तथा अप वित्तीय दायित्वों का सम्यादन । इसके अतिरिक्त काउण्टी राज्य प्रशासन की इकाइयाँ हुआ करती हैं। काउण्टिया ही याय, निर्याचन एवं कर सगठन की इकाइयाँ होती हैं। अपने कार्यों के सम्याध्य मं काउण्टिया को नियम एवं उपनियम बनाने का अधिकार होता है। प्रत्येक काउण्टी मं जनेक विभाग होते हैं। इत्य प्रमुख कल्याणकारी विभाग होता है। अपनेक काउण्टी मं जनेक विभाग साम काय-कुश्वलता का हास हुआ है सपा अपन्यम एवं वरवादी बढी है। काउण्टी के विभिन्न कार्यों भ वास्ति समव्य एवं संयुक्त निर्देशन का अभाव है।

दाउन (Town)—टाउन प्रमुख रूप से प्रामीण स्थानीय शासन की इकाई है। प्रपानत तीन प्रकार क टाउन होत हैं ग्राम, नाव एव बातपास के क्षेत्र, तथा नस्वा। यह व्यवस्था मूल रूप म अमरिका के यू इसर्वज्व म पायी जाती है। टाउन की एक समिति होती है। इसना वार्षिक अधिवेदान होता है। आवरयकतानुसार इसके किरोप अधिवदान भी आहूत किय जा सकत है। कम जनसर्या वाली टाउन मीटिंग म समी मतदाता माग तेत है। वहे टाउन म क्षेत्रीय समितिया द्वारा निर्वाचित प्रति निधि माग तेत है। विगय समितियो का स्थानीय मामलो की व्यवस्था का अधिवार होता है। इन समितियो द्वारा नियम बनाये जाते हैं, व्यय निधारित किया जाता है, कर लगाय जात है तथा ऋषा की स्थीकृति दी जाती है। नवीन स्कूला नी स्थापना म सम्बन्ध म निषय जात है। अपन क्षेत्र के लिए एक विद्यास्य परिवर्ष (Board of Sclect men) जिल टाउन काउ सल कहत हैं, तथा दिशा बोड के सदस्यों का निर्वाचित निया जाता है।

टाउनिशप (Township)-- मू इगलण्ड को छाडकर अनेक राज्या (ओहियो

⁸ Ibid p 395

नदी के उत्तरी एव डेकोटाज (Dacotas) व कनसास (Kansas) के पूववर्ती क्षेत्र क ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सासन की इकाई टाउनिया है। प्रत्येक टाउनियाप में एक निर्वाचित विद्यार में एक निर्वाचित विराय से बोहे होता है। इरियन प्रमुख अध्यक्ष (President) या महापौर (Mayor) या समापति (Chairman) नहाता है। परियद कमचारियों की निपुक्त करती है, वब्द पारित करती है तथा नियमा का निर्माण करती है।

टाउनियाप म अनेक कमचारी होते हैं। इनमें से बहुत से नमचारियों का कोइ दायित्व नहीं हाता है। लेक्नि जिन कमचारियों के दायित्व होते हैं वे अपने क्षेत्र म सानाराश होते हैं। टाउनियाप में टुस्टी सबसे शक्तिशानी अधिकारी होता है। प्राय यह सानाय मत है कि यदि टाउनियाप को समाप्त कर दिया जाय तो जनता को इससे लाम ही होया।

ग्राम सर्वेस छोटी स्थानीय इकाई है। इसका खासा ग्रामसमा (Village-Meeting) करती है। गाव मे एक परिपद, एक अध्यक्ष एव कुछ निर्वाचित अधिकारी होते हैं।

नगर (Cities)—संयुक्त राज्य अमरिका मे विषत एव वतमान धताब्दी म नगरो की जनसम्या म असाधारण बृद्धि हुई है। देश की 65% से मी अधिक जनता नगरा मे निवास करती है। नगर अमरिका के स्वातीय श्वासन की महत्वपूण इकाई है। यह काउन्छी का घहरी उपविचाग है। इसकी स्थित इगलण्ड के बरा (Borough) या काउन्टी बरो (County Borough) जसी है। अनेक बड़े नगरो के बारा कराईट छोटे नगरो का उदय हो गया है। व्यक्ती सफाई एव अय सेवाएँ, उनका प्रशासन तथा शान्ति गव व्यवस्था, नगर का प्रशासन जादि सम्बप्ति अनेक समस्या है। इसके अतिरिक्त इन दायित्वो क लिए वित्त की आवश्यक्ता भी है। इन सभी समस्याज का प्रणव समाजन नहीं हुआ है।

काउण्टी की मीति नगरो की भी स्थापना राज्यो द्वारा की जाती है। अत नगरा का धासकीय मगठन एवं शक्ति प्रत्यक राज्यों की इच्छा पर निचर होती है। इस सम्बन्ध में विभिन्त राज्यों द्वारा विभिन्न नियम बनाये गय ह।

नगर शासन का सगठन--राज्या के द्वारा नगरा की स्वापता के लिए मिन-भिन नियम निर्धारत किय गये हैं। नगरपासिकाओं को मिन मिन सक्तिया प्रदान की गयी है लेकिन जहाँ तक उनके सगठन का प्रदन है उसम कोई विश्तेप अन्तर नहीं है। नगरपासिकाओं के सगठन के सम्युण देख में निम्न तीन रूप हैं

(1) मेपर क्राउन्सल शासन (Mayor Council Government)—नगरा म यह स्थानीय शासन का सबस प्राचीन रूप है। इसम एक मेयर (महापोर) एव एक परिवद होती है। भगर मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया जाता है। उसका चाय

⁹ Zink and others op cit, p 41

काल 2 से 4 वप तक होता है एव उसे मासिक वेतन दिया जाता है। कुछ नगरो म मेयर निदलीय आधार पर चुने जाते हैं पर तु सामा यत वे दलीय आधार पर निवाचित होते हैं। कुछ नगरो म मेयर बक्तिशाली होते हैं और परिपद कमजोर होती है, तो कुछ म परिपद शक्तिशाली और मेयर कमजोर होते है। मेयर चाहे परिपद की अध्यक्षता करे या न करे, वह परिपद से निकट सम्पक रखता है। कुछ परिपदी में मेयर ही परिषद की अध्यक्षता करता है। जनेक नगरों में वह बजट भी तैयार करता है। बड़े नगरा म मेयर के बहुदायित्व होते हैं। उसे कुछ स्थितियों में कमचारी को पदच्युत करने का अधिकार भी प्राप्त होता है।

19वी सदी के अंत मे परिपद का स्वरूप द्विसदनीय था लेकिन अब एक सदनीय है। इसमे 5 से 50 तक सदस्य होत हैं जो मतदाताआ द्वारा निर्वाचित होते हैं। जिन परिपदो में संयर परिपद की अध्यक्षता नहीं करता है जनके अध्यक्ष चुने जाते है। सामायत परिषद का अधिवेशन माह मे दो बार होता है एव वडे नगरी मे प्रति सप्ताह । परिषद के काय स्वास्त्य, सुरक्षा एव नैतिकता सम्बाधी अधिनियमी का निर्माण करना, कर लगाना, ऋण लेना एव व्यय की व्यवस्था करना है। विभिन्न नगरा की परिषदों के दायित्वों में भी भेद होता है।

(2) काउ सल-मनेजर शासन (Council Manager Government)-इस प्रकार के स्थानीय शासन मे नगर परिषद (city council) प्रशासन के सम्पादन हेतु एक सवेतन प्रव धक या भैनेजर को नियुक्त कर देती है। वह नगर परिपद के प्रति उत्तरदायी होता है। वही प्रशासन का सचालन करता है। यह प्रणाली अधिका-धिक लोकप्रिय होती जा रही है। करीब 16 हजार से भी अधिक नगरा मे यह प्रणाली प्रचलित है। नगर परिपद द्वारा नीति निर्घारित की जाती है एव उस पर वह विचार विमश करती है। वह प्रवाधक भी नियुक्त करती है। प्रवाधक नीति का सर्चा लन करता है। समिति का कायकाल प्राय 4 वप होता है इसमे सामा यत 5 से 9 तक सदस्य होते है जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चुन जाते है। यह प्रबाधक प्रणाली व्यापार प्रणाली के सचालका (Board of Directors) एव मैनेजर के सम्बाधी पर आधारित है।

समिति प्रस्ताव पारित करती है, व्यय को स्वीकृत करती है, ऋण एव करी भागा निर्मात कार्या कर के हिन्दु कर कि है। विश्व है । विभिन्न कि व्यवस्था करती है। विभिन्न विद्यार अब कर के नियुक्त करते समय स्थानीयता का व्यान रखा जाता है पर तु योग्य व्यक्ति ही सामा यत चुने जाते हैं। वाहर के व्यक्तिया म स मी प्रव मको का चयन निया जाता है। यह प्रणासी करीब 40 वर्षों से प्रचलित है। कनसास नगर एव नतीवतण्ड के ब्यनुमची के बाधार पर यह कहा जा सकता है कि

इस प्रणाली म दलीय नतावा का वाधिपत्य रहता है।

(3) कमीशन फाम नगर शासन (The Commission Form of City Government)--इसप्रकार क नगर शासन म एक आयोग नगर का शासन चलाता है।

आयोग के द्वारा विधायों एवं कायपालक दायित्वा का सम्पादन किया जाता है। मदस्य गणों को दो से चार वप के लिए निर्वाचित किया जाता है। इनमें से एक को मेयर चुना जाता है। प्रति सप्ताइ एक या दो अधिवेदान होते हैं। सभी सदस्यों द्वारा नीति-निर्योग्ण, करारोपण एव ज्यय व्यवता नृत्व निर्योद्ध एवं प्रस्तावित किये जाते हैं। इसके अतिरक्त वजट फारिक करना एवं अधिकारियों को नियुक्त एवं परच्युत करना भी आयोग का ही काम है। विभिन्न सदस्य विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं।

आयोग प्रणालों के अनेक दोष प्रकाश में बाये है। इनमें काय म एकस्पता नहीं होती है। प्रशासकीय अनुभव से विचत होने के कारण सदस्यण विमिन्न विमागी पर पूज नियानण रखने में असफल रहते हैं। यह प्रणाली पहले की तरह लोकप्रियं नहीं है।

स्यानीय शासन की अन्य इकाइया¹⁰

दक्षिणी पश्चिमी कुछक राज्यों में कार्जाण्यों को मैजिस्टीरियस जिला प्रांस-कृत्म (Precincis), निर्वाचित जिला एव स्था में विमाजित किया जाता है। इनका सर्पाटत पासन नहीं होता अपितु निर्वाचन के लिए केवल काउच्छी के विमाग मान होते है। इसके अंतिरिक्त एक ज्या इकाई—विवेध जिले—मो है। इस इकाई का अधिक प्रचलन नहीं है। सामायत विदोध विने पाच प्रकार के हाते है—धार्शणिक मफाई (Sanitary), जलीय, मावजनिक उपयोगिता सम्बर्धी एव अप ।

¹⁰ Harold Zink and others op cat 1967 pp 412-414

¹¹ Ogg and Ray Essentials of American Government, 1964, p 669

एक उदाहरण यह ह नि 'निगेष जिला को कर, व्यय एव ऋण सम्बाधी अधिनार है। विशेष जिला ने इन जनर कार्यों को काउण्टिया, नगरा एव धासन को जाय इना-इया को सापा जाना चाहिए तभी स्थानीय शासन से मितव्ययता एव क्षमता की आशा की जा सकती है।³²

भारत में स्थानीय शासन

भारत य स्वानीय सस्वाएँ नवीन नही हैं। प्राचीन कास म ग्राम-पचायतें थी और उस समय ग्राम अपन-अपने क्षेत्रा म पर्याप्त स्वायत्त सम्पन्न थे । ग्राम-पत्तायती व्यवस्था त्रिटिश शासन के प्रारम्भ तर विद्यमान रही थी । लेकिन वतमान भारतीय स्यानीय शासन ब्रिटिश शासन की देन है। ब्रिटिश काल म ही 1687 ई म मद्रास कॉर-पोरशन की स्थापना की गयी थी। इसी के साथ भारत म स्थानीय स्वदासन का प्रारम्म हुआ। 1793 ई के चाटर अधिनियम द्वारा शान्ति यायाधीश (Justice of Peace) की नियुक्ति की व्यवस्था की गयी थी। इन्हें सहका की स्वच्छना एवं मरम्मत के निए वर लगाने एव शराव की विश्री के लिए लाइसन्स दन वाले इन्सपैक्टरा की नियक्ति का अधिकार दिया गया था। 1842 ई म कलकत्ता के अतिरिक्त बगाल क अय नगरा में भी स्थानीय स्वदासिन का प्रारम्भ हुआ था। लेकिन मारत म स्थानीय स्व शासन का वास्तविक प्रारम्भ 1882 ई म लॉड रिपन के द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव सं होता है जिसके अत्तरह स्थानीय संस्थाजा को अधिक स्वत प्रता देन ग्रामीण क्षत्रा में स्थानीय शासन की स्थापना, सदस्या के निर्वाचन तथा इन सस्याजा पर चनतम शास कीय निय नण का सुभाव दिया गया था। 1907 ई म विकेदीकरण आयोग ने ग्राम पचायता की स्थापना का सुभाव दिया । प्राचीन पचायत व्यवस्था से वतमान स्थानीय शासन व्यवस्था का कोई सम्बाध नहीं है । ब्रिटिश शासन के अन्तन्त स्थापित स्थानीय शासन श्रमिक विकास का परिणाम है और स्थानीय शासन की सस्याओं के कायक्षेत्र एव अधिकारो म धीमी गति स वृद्धि हुई है। यह पूणत लोक्तात्रिक भी नहीं है। सरकारी पदाधिकारियो (जिलाधीश एव आयुक्तो) को निय त्रण के व्यापक अधिकार प्राप्त है। इनके विसीय अधिकार भी सीमित है। नगरमहापालिकाएँ (Corporations), नगरपालिकाएँ, नोटीफाइड एरिया एव टाउन एरिया, क टूनमे ट बोड, भोट दूस्ट, इम्प्रबमें ट ट्रस्ट (Improvement Trust), स्थानीय शासन की शहरी इकाइया हैं। नगरपालिकाएँ (Municipalities) A, B और C तीन प्रकार की होती हैं। ग्रामीण क्षेत्र से सम्ब वित स्थानीय शासन की निम्न इकाइयाँ हैं जिला परिषद (District Boards), ताल्लुका बोडएव ग्रामीण पचायत । स्वत जता के पूव केवल कुछेक प्राती मे ही ग्राम पचायती व्यवस्था थी।

काँरपोरेशन (Corporation)

महापालिकाण केवल बढ़े नगरा मं ही पायी जाती हैं। बम्बई क्लक्ता एव

¹² Harold Zink and others op cit, p 414

मद्रास की महापालिकाएँ प्राचीन है। उत्तर प्रदेश म लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर एवं वागरा^भ्र महाराष्ट्रं म वस्वई एवं नागपुर, मध्य प्रदेश म जवलपुर, एव स्थानीय शासन | 991 विहार म पटना तथा दिल्ली म महापालिकाएँ हैं। महापालिका एवं नगरपालिका म चित्रियो एव कार्यो तथा दायित्वा के सम्ब ध म अ तर है। महापातिका की स्थापना पाणना एवं विधानमण्डल की विधि द्वारा की जाती है। नगरपालिकाओं की स्वापना सम्बन् िपत स्वानीय शासन अधिनियम के अधीन राज्य सरकारी द्वारा की जाती है। महा पालिका का अध्यक्ष महापोर (भयर) होता है। इसकी जनसत्या नगरपालिकाओं से अधिक होती है और महापातिकाओं को अपेक्षाकृत अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है है।

महापालिका म दो प्रकार के सदस्य होते हैं समासद एव वडजन (Eldermea)। उत्तर प्रदेश की महापालिकाओं म विनिष्ट सदस्या की सक्या समासवी की 1/9 होती है। समासद जनता द्वारा वाडों क साधार पर बुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश म महापीर को उसी नगर का निवासी एवं 30 वप से अधिक आयु का होना चाहिए। त्र महारार का एका एकर का होता है अर्थात वह प्रति वस चुना जाता है। एक उपसहा-विषया भाषणाण देश वर्ष होता है। ज्यममुख का कायकाल 5 वप होता है। महा-पालिका म दो प्रमुख समितिया होती है कायकारिणी समिति एव विकास समिति। कायकारिणी समिति महापालिका की कार्यपालिका समिति होती है। इसे निज्ञ, त्रामा य प्रशासन के निरीक्षण एव निय त्रण के अधिकार होते हैं। विकास समिति ो सामा य विकास, आवास सडके एव जनका विकास, सफाई एव पुनिनामिण के ा चाना व विकास अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त एक युरम नगर अधिकारी या स्त्रुनिस्तित किमश्नर भी होता है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। भहापालिकाओं को विजिन्न प्रकार के कर समाने का अधिकार होता है,

जस—सम्पत्ति पसु यातायात साधना गाडियो एव अय वाहनो एव पसुआ पर कर, ब्यापार एव व्यवसाय कर, विज्ञापन, वियेटर एव भूमि की मूल्य वृद्धि पर कर आदि। उत्तर प्रदेश की महापालिकाओं के 38 प्रकार क अनिवास एवं 43 प्रकार के रैं च्छित काय हैं। अनिवाय काय निम्नत हैं सडका का निर्माण एवं गरम्मत, बसे प्राच्छा भाव है। भागवान भाग भाग है कि स्वाद्य की स्वाद्य की स्वाद्य की स्वाद्य की स्वाद्य की स्वाद्य की स्वाद्य रोधनी स्वच्छ जल का प्रब घ, महामारियो को रोकना, चिकित्सालया एव जिसु विचा लया का प्रवाध आदि।

उत्तर प्रदेश में राज्य शासन की महापालिकाओं को विषटित करने का भी अधिकार है। यदि राज्य शासन अनुमव करता है कि जनक द्वारा अपन अधिकार का ारमार १८ राज राज वाराज वार इरुपयोग किया जा रहा है और ने अपने कार्यों को करने में असफल हैं तो महापानिका

¹³ इन नगरा में नगरमहापालिकाओं की स्थापना 1958 ई म राज्य अपिनियम्

को विषयित करने उसका निय नण अपने हायों में न सकता है। परन्तु ऐसी स्थिति म 6 माह के मीतर पुन निर्वाचन होना आवश्यक है। राज्य सासन को महापालिका के हर विमाग एवं उसके कागजाता के निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। नगरपालिकाएँ (Municipalities)

देश मर म करीब एक हजार नगरपालिकाएँ हैं। सबप्रथम नगरपालिका की स्थापना 1887 ई म हुई थी। उत्तर प्रदेश मे करीव 137 नगरपालिकाएँ हैं। उत्तर प्रदेश म प्रथम बार 1916 ई में नगरपालिकाओं की स्थापना की गयी थी और प्रथम नगरपालिका अधिनियम पारित किया गया था। इसकी सदस्य सख्या 15 से 60 तक होती है। इसके सदस्य निवांचित होते है। उत्तर प्रदेख के 10 हजार से अधिक जनसस्या वाले नगरा म नगरपालिका स्थापित की जाती है। इसके सदस्या द्वारा एक अध्यक्ष एव उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। इसके अतिरिक्त अनेक पदाधिकारी होत हैं जिनमे प्रमुख कायकारी अधिकारी (Executive Officer) होता है। छोटी नगरपालि काओं म इसे सचिव (Secretary) कहते हैं। जल विमाग की देखमाल जल कल अभिय ता करता है। कुशल प्रशासन के लिए समितियों का भी निर्माण किया जाता है। नगरपालिकाएँ सबसाधारण की सुविधा, स्वास्थ्य रक्षा, शिक्षा आदि काय सम्पा दित करती हैं। पानी, विजली, यातामात के लिए वसी की चलाना एवं सिनेमा गृहां का प्रवाध करना इसके अय काय हैं। इनकी आय के प्रमुख साधन है, चुगी, सम्पत्ति कर. मकान, जमीन-जायदाद, व्यापार एव पद्मापर कर,सडक वाहन,पशुओ एवयात्रिया पर कर। इसक अतिरिक्त राज्य शासन से अनुदान भी प्राप्त होता है। राज्य शासन का इनक निरोक्षण एवं नियं यण की चवित प्राप्त है। अगर नेगरपालिका द्वारा अपने दायित्य को मली प्रकार सम्पादित नहीं किया जाता है तो राज्य शासन को उस निल म्पित करन क अधिकार हैं।

अ'य शहरी स्थानीय सस्थाएँ

जिन वस्ता की जनसम्या 10 हजार स 20 हजार तक होती है वहाँ वी स्थानीय सस्या को टाउन ऐरिया (Town Area) वहत हैं। इसम एक नेयरमन, पीच से सात तक निर्वाचित सम्या एव दो मनानीत सदस्य होत हैं। इनका कायवास 4 वप हाता है। 5 से 10 हजार तक जनसम्या जाने वन्स्या म नाटीवाइड एरिया (Notified Areas) को स्यापना की जाती हैं। इसम तीन से पौच तक मदस्य होने हैं एय एवं चेयरमैन होता है। इसक सदस्य या ता मतनाताओ द्वारा निर्वाचित होते हैं एय एवं चेयरमैन होता है। इसक सदस्य या ता मतनाताओ द्वारा निर्वाचित होते हैं । सरकार विभाग निमनर द्वारा मतोनीत। इन समितिया व अधिकार सीमित होते हैं। सरकारी अधिवारी—मण्डतायोग्र (S D D)—इनो वाय वा निरोक्षण चरता है।

केट्नमेच्ट बोड (धावनी)—वर्ड नगरा म एत शत्र होत हैं वहाँ सना रहती है। व नगरगातिका र क्षेत्राधिकार न बाहर होत हैं। दा क्षेत्रा म जेट्नमण्ट बाढ

की स्थापना की जाती हैं। इसका समापति कोई फौजी अधिकारी होता है। वे टून मण्ड बोढ के दायित्व व कतव्य सामा यत नगरपालिका के सहस्य होते हैं।

षोड ट्रस्ट (Port Trust)—समुद्रतटीय नगरा के क्षेत्रा की देखमाल के लिए इनको स्थापना की जाती है। कलकत्ता, महास आदि नगरा मे पोट ट्रस्ट स्थापित किय गये है।

बढे वडे नगरा के विकास, जर्नात एव सुघार के लिएनगर सुघार थास (Imp rovement Trust) की स्थापना की जाती है। इसके सदस्यों को प्रा तीय शासन, नगर-पालिकाओं एवं व्यापारिक संस्थाओं द्वारा तीन वप के लिए मनोनीत किया जाता है। इन सदस्यों हारा अपने में से ही एक अध्यक्ष चुना जाता है। इनका काय नगर विकास की योजना बनाना एव किया वयन होता है। स्वत नता के परचात भारत के प्रामीण क्षेत्र भे स्वानीय शासन

मारतीय सविधान निर्माता महात्मा गाधी की पचायती व्यवस्था की धारणा ते प्रमावित वे । फलस्वरूप राज्य कं नीति निर्देशक तत्वो में प्रचायती व्यवस्या की त जनाभव व । क्यान्यक्य प्रथम के भाग मानवास प्रथम के स्थापना पर बल दिया गया है (अनुच्छेब 40) । त्रयम, दितीय एवं ततीय पचवर्षीय योजनाओं मं भी निरतर भ्राम पंचायतों की स्थापना पर बल दिया जाता रहा है। पाणाणा च वा १९८८ अस्य उचावता चा रचाउठा उर् चणावता चाता रहा है। द्वितीय प्रचवर्षीय योजना के अनुसार श्राम प्रचायतो का सही दिशा में विकास कार्र हिराज र राजार में महत्त्वपूर्ण हैं।" ततीय पचवर्षीय योजना म क्षेत्रीय एवं ग्राम प्वापता को भारता च गहरत्रत्र हा अक्षान निवास के अभावकारी उपकरणा के कप म स्वीकार किया गया। योजना आयोग ने समुदायिक विकास एव राष्ट्रीय प्रसार परियोजनाओं के सम्बन्ध म एक अध्ययन सम्रह की नियुक्ति सी बलवन्तराय मेहता की अध्यक्षता म की थी। पण अञ्चल एवर मा गाउँ पण जा अवस्था मा वह कहा गया था कि व्यापक क्षेत्र की स्पानीय ्ष्या अवस्यकताला एव स्थानीय परिस्थितिया के प्रति सोकत शीम सासन के निए याम करना कठिन है। अत समिति ने यह प्रस्तावित निया पा कि विकास कार्यों म प्रामीण जनता की हिंच जागत करने के लिए शासनत न को विकेटित करना आवश्यक है एव ऐसी लोकताित्रक प्रतिनिधि संस्थाया की स्थापना की जानी चाहिए जिह पर्योत्त शक्ति एव यन प्राप्त हो और जिह स्थानीय लक्ष्या क अनुसार पन के ध्य पर आवस्यक निरीक्षण एव निर्देशन भी प्राप्त हो। अस समिति ने राज्य-स्तर स ब्यव पर आवष्यका । पर्याचन प्रमाणिक वा नाम व्याचन व्याचन विकास वि करण है। इसम धासन के निम्म स्वरो एवं स्थानीय अभिकरणा को धासन सत्ता के प्रयोग सम्बंधी निषय स्वयं करने के अवसर प्राप्त होते हैं। तोनताश्विस विन्द्री करण म जनता का पहल एव उत्तरदायित्वपूष रूप से काम करने न अवसर शास्त होत हैं। लोकता त्रिक विके डीकरण म निम्म सस्याओ एवं अनिकरण की आन्तरिक स्तत त्रता पर अधिक बन दिया गया है, कवन सत्ता क विक ट्रीवरण या हस्तान्तरण पर नहीं।

मेहता समिति न निम्न वातो पर विशेष वल दिया था

- (1) निर्वाचित स्वशासन सस्याबो—पद्मायत समितियो—की स्वापना की जाय। साथ ही साथ विकास-खण्ड के स्तर पर क्षेत्रीय समितियाँ होनी पाहिए वो पद्मायतो द्वारा अत्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित हो। इन समितियो को ग्राम पद्मायता के वजट की स्वीकृति एव निरीक्षण के अधिकार होने चाहिए।
- (2) अपने क्षेत्र म समी विकास-कार्यों के निरीक्षण सम्बंधी कुछ काय एवं वायिक्त इन निकायों को दिये जाने चाहिए ।
- (3) ब्लॉक क्षेत्र मे विकास की धन राशि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से केवल पचायत समितियो ढारा ही व्यय की जानी चाहिए ।
- (4) विभिन्न पचायत समितिया के कार्यों भ समावय के लिए जिला परिपद का निर्माण किया जाना चाहिए।

अत मेहता समिति ने जिला म ग्राम, ब्लॉक एव जिला अयात जिस्तरीय स्थानीय सस्थाओं की स्थापना का सुभाव दिया था। विकेद्रीकरण की वतमान व्यवस्था को समाप्त करके उनके स्थान पर नये निकाया (bodies)--ग्राम पनायत, विकास लण्ड की समिति एव जिला परिपद-का सगठन प्रस्तावित किया था। विकास खण्ड समिति विकास खण्ड (Development Block) से सम्बर्गियत हो, प्रत्येक विकास खण्ड के सभी गावों को ग्राम पचायत से तथा छोट-छोटे गाँवा को एक ही गाव पचायत से सम्बद्ध होना चाहिए । जिला-स्तर पर जिला वोड होने घाहिए। प्राम पचायत एव विकास खब्ड की पचायतो से सम्बद्ध क्षेत्र की जनती को प्रत्यक्ष रीति से इन निकाया के कार्यों म अधिकतम भाग लेन के अवसर होने चाहिए । जनता को जन-करमाण से सम्बद्ध योजनाओं को प्रस्तावित एव स्वायत्तता पूरक विकास योजनाओ को सचालित एव कियाचित करने के अधिकार होने चाहिए। महता समिति न विकास कार्यों के लिए लाकता निक विवेदीकरण का प्रस्ताव करते हुए कृषि, पशुपालन, स्वास्य्य एव सप्पाई, चिकित्सा, ग्रामीण उद्याय, प्राथमिक शिक्षा, स्यानीय यातायात, लघु सिंचाई एव स्थानीय सुविधाओ आदि कार्यों को इत सस्याओं के क्षेत्रीय निकामों को देन का प्रस्ताव किया या। अस लोकसानिक विवेदी करण का अब यह है कि स्थानीय मामलो का प्रबाध उस क्षेत्र की जनता द्वारा किया जाना चाहिए। लोकता निक दिक दीकरण निम्नस्तरीय सस्याओ एव निकायों की सत्ता के साथ उत्तरदायित्व, पहल एव स्वायत्तता के विष्कमण का सिद्धान्त है। विकास कार्यों की सफलता स्वेच्छित जन सहयोग पर ही निभर है।

मेहता समिति द्वारा प्रस्ताबित लोकता त्रिक विकेदीकरण की योजना को सबप्रथम राजस्थान राज्य मे लागू किया गया। 2 अक्टूबर, 1959 ई को राजस्थान म प्रिस्तरीय प्रचायती व्यवस्था की स्थापना की गयी थी। ग्राम प्रचायत सबने छोटी इकाई है। इसना प्रमुख सरपथ होता है। इसके अनिवाय काय जल, सफाई, चिकिस्सा,

पारिमक ज्ञिला, कृषि मं सहायता एव लघु तिवाई योजनाओं की व्यवस्था करना है। इहें भूमि-कर बसूब करते का काय भी तींचा गया है। ग्राम पंचायती के ऊपर स्थानीय शासन | 995 यतो के सरपच शामिल होते हैं । इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले की एक परिपद होती है जिसे जिला परिपद कहते हैं। इसका मुख्य काय प्चायत समितियों के बजट का परी-व्यव व्यवस्थित वास्त्र विष्णु है। रेक्का उठक काल व्यवस्थ कामाध्य के कार्यों के समय तथा प्रवास्त्री प्रवास्त्री ध्यात्र अपने प्रमाणक प्रमाणक विकास के सम्बन्ध में राज्य शासन को प्रामस देना है। जिला परिपद अपने क्षेत्र म काफी स्वायत्त सम्प्रज है। राज्य सरकार का इन प्रचायती सस्याओं के अपर काफी नियानण होता है। राज्य शासन इहे विषटित करके उनके कार्य जिलाघीस को भीष सकता है। इन ह्यक्तियों का उद्देश्य अध्यवस्थित प्रचायती सस्याओं के मामले म हस्तक्षेप करना है।

नतर प्रदेश म पचायती राज्य का प्रारम्य 1 जुलाई, 1963 से हुँ*या है*। इस सम्बन्ध में 1961 ई म उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एव जिला परिपद अधिनियम पारित किया गया था। मई 1958 ई में उत्तर प्रदेश शासन ने जिला परिपदी की मग पारत क्षा प्रथा भा । वर 1220 र च २०४८ अथस साराच च १४४४। भारत स्वा स्व करके अ तरिम्न जिला परिपदा का निर्माण किया था। ग्राम पचायती व्यवस्था के तीन अंग हैं—प्राम समा, ग्राम प्रवायत एवं प्रवायती अवालत या याय प्रवायत। ग्राम जा १ - आग प्रमान के अधार है। राज्य म करीव 72428 ग्राम समार है। प्राम प्रवायत गांव की कायकारिणी होती है। याम तमा गांव की व्यवस्थापका हैं। चार या पाँच ग्रामों की एक याय पंचायत होती है। इसे सीवानी एवं फोजदारी कर सकती है।

वाम समा, वाम पनायत एव याय पनायत पर राज्य सरकार की निय त्रण के व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। उसे याम समा के कार्यों का निरीक्षण करने का अधि कार है। वह इन सस्यामा की जान कर सकती है। जिला परिपद के कार्यों का भार १ नव का वरनाचा भारता है। वासम्ब की व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। चिक्तिया के डुक्पयोग की अवस्था म शासन जिला परिपद को मग कर सकता है।

प्रामी म ब्याप्त असिक्षा, णातिवाद, निधनता के कारण पंचायती व्यवस्था सफल नहीं हुई है। प्रचायती व्यवस्था के बीज जनता म होने चाहिए पर तु मारत म ऐसा नहीं है। एक प्राचीन सस्या होते हुए भी नवमान समय म इसकी धासन हारा नामान कारण हैं। पनामती व्यवस्था की असफतवा के प्रधान कारण हैं। पनामती व्यवस्था के प्रतित्वस्य प्रामीण क्षेत्रो मं गुटव दी, माई मतीजावाद, नमहे एव वैमनस्य म वृद्धि 野青 青月

सोवियत सघ मे स्थानीय शासन

आग एवं जिंक¹⁶ के अनुसार जारकालीन रूस प्राचा, कालिण्यो, कैण्टना, एव ग्रामीण जिला म बिमाजित था। लाल फाति के पश्चात साम्यवादिया ने जार कालीन शासन का व्यायक पुनगठन किया है। सोवियत रूस म गावा एव शहरा की म्युनिसिएल सावियत है। ¹⁷ इन सोवियतो के जनर जिला—रायोन (Rason)—हैं। प्रत्येक रायोन म 20 25 ग्राम्य सावियतो या 1 से 3 शहरी सोवियतो के नेन हाते हैं। रायोन के कपर की इकाई आव नास्ट (Oblast) होती है। बोबलास्ट (Oblast) ने पुरानी इसी प्राचा ने स्वाय से ति वया है। क्षेत्र (territories)—स्वायत्त गणराज्य एव स्वायत्त केन्त्र को होते हैं। रायोन सावियत के सदस्य तीन वय के लिए मतदावाओं डारा निर्वाचित होते हैं। सामायत रायोन के सदस्यों की सरस्य 25 से 60 तक होती है।

रायोन सोवियत का एक प्रधान या समापति होता है। इसके अतिरिक्त प्रेसी हियम, कायकारिको समिति, एक मानी एव कई स्वायी समितिया होती हैं जो विशेष मामलो से सम्ब ित होती हैं जोस न्यायकारिक विश्वा विश्वा कि स्वायी समितिया होती हैं जो विशेष मामलो से सम्ब ित होती हैं जोस क्याया एव नागरिक व्यवस्था । अप समितिया की मी स्वापना की वा सकती हैं। रायोन के अपने कम चार होते हैं। अपने क्षेत्र के प्रामा एव शहरी सोवियतो पर रायोन का काफी निय नच होता हैं और इन सस्थाओं के कार्या एव योजनाओं को स्वीकृत या अस्थीकृत कर सकते हैं। अपने क्षेत्र के समामता म उ है पूण अधिकार होता है। लेकिन आग एव जिंक के अनुसार रायोन (जिंता) सोवियत की क्ष्य सोवियतों की शांति उच्चतर सोवियतों के अधीन होती हैं। वजट सम्ब प्रस्ताओं पर जिला सोवियतों को शांत उच्च अधिकारियों की स्वीकृति लेंगी पहली है। प्रस्ताओं पर जिला सोवियतों को भी उच्च अधिकारियों की स्वीकृति लेंगी पहली है।

शहरी सोबियत— रूस मे शहरा की सरमा म बिद्ध हुई है। इनकी अपनी म्युनिसिएल सोवियते होती है। इनम मी अप सोवियतो की मांति प्रधान प्रेसीडियम कामकारिणी समिति एवं अनेक समितिया होती हैं। इनकी सक्या 100 तक होती हैं। एक लाख या उससे अधिक जनसंख्या बारे सहरों को बादों में विमानित कर दिया जाता है। इनकी भी अपनी सोवियतें होती हैं। बाढ सोवियतीं का उद्देश्य विके ट्रीकरण करना एवं जनता का सामन के कामों से अपसाइत अधिक स्वानिकरण करना एवं जनता का सामन के कामों से अपसाइत अधिक संविद्ध से स्वानिकरण करना एवं जनता का सामन के कामों से अपसाइत अधिक संविद्ध से अधिक संविद्ध से अधिक संविद्ध से अधिक स्वानिक सम्बन्ध स्थापित करना है। बढ़े बढ़े नगरा का आकार एवं क्षेत्रकरों

Ogg and Zink Modern Foreign Governments, 1956 pp 913 914
 सािवात किसी क्षेत्र गाव, शहर, कारखाना, सिनक टूकडिया के प्रतिनिधियों की परिपद को कहते हैं। सोवियत में अधिको एवं सिनका ना प्रतिनिधियत होता है। परिपद का रूसों पर्यायवाची सावियत है।

¹⁸ Ogg and Zink op cit, p 914

विस्तृत होता है। फ्लस्करूप विके बीकरण के लाम उपलब्ध नहीं होत है। वडे नगरा वर्षण्य १९७१ १ , र अस्पर्य १५० आस्त्रर १५० अस्पर्य १९८० १ , १५० अस्पर्य १९८० १ , ४० अस्पर्य १९५० १ , ४० अस्पर्य की विभिन्न वार्डों की सोवियते भी इतनी वडी होती है कि वे सक्षमतापूर्वक नेपन कार्यों को सम्पादित नहीं कर पाती है।

यामोण सोवियतं भ्यावियतं रूस म ग्रामा की अधिकता है और उनकी संस्था तालो म है। छोटे छोटे यामो म मतदाता वप म 6 माह परचात एकत्रित पट्या पाला महा आट पाट मामा म मुक्ता पूर्व में हैं। ब्रामीण वीवियता (Selosomets) के लिए प्रतिनिधि चुनने हेंद्र व हर एक हात है। वह होते हैं। यह ग्रामीय समाएं रुसी समाज की जीते पुरानी व्यवस्था है और साम्यवादी सासन की कोई नवीन देन नहीं है। वैकिन स्वधासन के सन म ह जार पाल्यवाचा पाचम का भाव भाग चम महा है। यह ग्रामा की जयनी सीवियत होती है। विषका कार गहान्त्र न नामान गर्ध ए । यह भागा भा भागा हो। प्राप्त होटे गावा को मिलाकर तमुक्त सीवियत वनायी जाती है। प्रामीण सीवियता को कह खाट पाना चा पाना है. ''डण पाना चारा होते हैं। समूहिक इति सम्बन्धी हुई अथन कान म अवासक कारास्त्राह्म कार्य हार वा कार्य व्यवस्था होते हैं। ब्रामा म सहकारिता समितियों का निर्माण विद्या ब्दायक मायकार मान्य हाय है। माना न व्यक्तारका चानावया का नामाय ज्ञानाया है। विकिन उच्च सत्ता को ग्रामीय सोवियतो के कार्यो एव नीतियो को अस्थो-हत करने का अधिकार प्राप्त होता है। प्रत्यक ग्रामीण सोवियत म निर्वाचित प्रधान, विव एव अनेक अय अधिकारी होते हैं। इसने अतिरिक्त एक कायकारिणी समिति भी होती है। विभिन्न समितियों के द्वारा विभिन्न विषया सम्बन्धी कार्यों ना सम्पादन किया जाता है।

समीक्षा-पश्चिमी आलोचको हे अनुसार सोवियत स्पानीय पासन की सस्याओं को व्यवहार म स्वायत्तवा प्राप्त नहीं है। उनके हारा नीति निधारण सन्य था बहुत कम याय किया जाता है। उच्च स्तरीम सस्याभा क निम्मस्तरीय सावियता न कार्यों एवं नीतियों को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार है। सभी स्तरा पर कावा ५व मातका का त्वाक्रव का अरुवाक्ष्य मार्थिक मार्थिक वस्तु हो स्वापना की सभी है परंतु हमक सार्थिक स्वापना की सभी है परंतु हमक सार्थिक स्वापना की सभी है परंतु हमक सार्थिक स्वापना की सभी अमाव पाया जाता है। तोवियत रूस म एकदलीय व्यवस्था है। सोवियत मय म नियमण एव निरीक्षण का भाषार नोबतानिक वे बीवरण है। इसम नाबतान की कम के बीकरण को अधिक महत्व दिया जाता है। थिमक वग के हित म शासन एव वल द्वारा क त्रीकरण का अनुगमन किया बाता है। स्टासिन क अनुसार दल सावि-यता का नतत्व करता है। परन्तु वह उनका स्थान नहीं ने सकता और न उस एमा करता ही चाहिए। स्पन्ट है वि ग्रोवियत स्थानीय ग्रातन व दलाय तथा वजीव निय त्रण हो मुख्य विशेषताएँ हैं। साम्यवादी चीन म स्यानीय स्वशासन

साम्बनाता चीन म ग्राम निता राष्ट्रीय ग्राम निता बस्वा म्युनिसिप्त जिला एवं नगरपालिकार्यं मुख्य स्थानीय इंचाइयाँ है। बतमान सर्वियान (1954 है) 19 Ibid, pp 918 920

के त्रिया वयन के समय से चीन म प्रशासन के तीन स्तर है (1) विशेष नगरपालि-काएँ-3, (2) स्वयासित क्षेत-5, एव (3) प्रात-11। इन तीनो स्तरो की इकाइयो की प्रशासन व्यवस्था मे पर्याप्त समानता है। इनके शासन का स्वरूप के द्रीय शासन का प्रतिरूप है। प्रत्येक स्तर पर शासन के एक से अग--जन कांग्रेस, जन-परि पदे—होती है । जन-परिषद जन-काग्रेस द्वारा निर्वाचित एव उसी के प्रति उत्तरदायी होती है। निम्न स्तर पर जन काग्रेस राज्यसत्ता का स्थानीय अग होती है। ग्राम जिला, राष्ट्रीय ग्राम जिला, कस्वा म्यनिसिपल जिला एव नगरपालिका की कांग्रेस के सदस्या की मतदाताओ द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित किया जाता है। प्रत्येक स्तर की काँग्रेस के सदस्यों की सख्या उस क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार पृथक पृथक होती है। दो हजार जनसस्या वाले ग्रामीण जिले या कस्वे की काग्रेस में सदस्य तथा काउण्टी काग्रेस में 30 से 450 तक सदस्य होते है। प्रातीय काग्रेस मे 50 से 600 तक सदस्य होते हु। लेकिन शहरी क्षेत्रा की ग्राम्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। ग्रामीण जिले मे 2000 जनसंख्या के पीछे एक सदस्य निर्वाचित किया जाता है। लेकिन शहरो म 500 व्यक्तियों के लिए एक प्रतिनिधि निर्वाचित किया जाता है।

स्थानीय जन काँग्रेसो का काय स्थानीय आर्थिक एव सास्कृतिक विकास तथा सावजनिक निर्माण की योजनावा का निर्माण स्थानीय बजट एव वित्तीय प्रतिवेदनी का परीक्षण, सावजनिक सम्पत्ति की रक्षा तथा नागरिक एव अस्पसस्यको के अधि कारा की रक्षा करना है। ये काननो को कियायित करती हैं एव उनका पालन कराती है। स्थानीय काँग्रेसो द्वारा अपने से ऊँची काँग्रेसो के सदस्या को निर्वाचित किया जाता है। उन्हें अपने सदस्यों के प्रत्यावतन की माग करने का अधिकार है। निम्न जन-काँग्रेसो के निणया के परीक्षण एव उन्हें निरस्त करने की उन्हें शक्ति होती है ।

जन-परिपद मे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एव सदस्यगण होते है । विमिन स्तरो की जन परिपदी म पदाधिकारियो के नामा में बन्तर होता है, यथा-प्राप्त में उन्ह गवनर एव डिप्टी गवनर, नगरपालिका मे मेयर एव उप मेयर, काउण्टी मे मजिस्ट्रेट एव उप मजिस्ट्रेट, ग्रामीण जिले मे हैड (Head) एव डिप्टी हैड (Deputy Head) कहते ह । स्यानीय जन परिपद स्थानीय जन काँग्रेस की कायपालिका अस होती ह । जन कार्येस एव जन-परिषद का प्रत्येक स्तर पर कायकाल एक समान होता है। प्रान्तीय परिषद एवं कांग्रेस का कायकाल चार वप एवं अय सभी कांग्रेसो एवं परिषदी की कायकाल दो वप होता है । परिपदा को काँग्रेस एव शासन के निणया एव आदेशी की फ्रिया वित करना, काँग्रेस का निर्वाचन कराना एवं अधिवेशन आहत करना तथा वृद्धिस के समक्ष विधियों की प्रस्तावित करना होता है। कांग्रेस के समावसान-काल म परिपदा के द्वारा ही निणय किये जात है एव वे ही आदेश जारी करती है। परिपद की यासिया को देखते हुए यह कहना कही अधिक ठीक है कि परिवर्दे न कि स्थानीय कियम अपने क्षेत्र में सासन के प्रयानकारी अभिकरण हैं। सोवियत इस की उन्ह चीन मं भी लोकनान्त्रिक के द्रीवरण के मिद्धात्त को सासन के हर स्तर पर मायना प्राप्त है।

कम्पून व्यवस्था

चीन की कम्यून व्यवस्था स्थानीय शासन की गुरूष विशेषता है। 1958 दें म कम्यून स्थानका के स्थापना के लिए राष्ट्रस्थायी खारांतन चलाया गया था। एनलस्वरूप रितरस्थ 1958 है म चीन के 90% कुपक वरियारों ने अपने की 23348 जन करंग्रेसा में सगठिन कर तियाया। पहले प्रत्येक कम्यून से औसतम 4797 परियार होते वे लेकिन वतमान य औसतन 6 स 7 हजार तक परियार प्रत्येक कम्यून में होते हैं। एक कम्यून में 2000 से 20,000 तक परियार प्रत्येक कम्यून में होते हैं। एक कम्यून में 2000 से 20,000 तक परियार सम्मित्त हो सकते हैं। कृपि सहकारिताओं की सम्पत्ति एय सामग्री कम्यून को हस्तायरित कर दी गयी हैं। सहकारिता सथ के प्रत्येक सस्य द्वारा अपनी भूमि, पन एव उत्यायन के अप सामग्र पन् पेक आदि कम्यून को सौंप दिये गय है। विशेष परिस्थितियों म क्यांतिगत सदस्यों को कुछ यालतू यद्यु एव व्यक्तिगत सदस्यों को कुछ यालतू यद्यु एव व्यक्तिगत सम्पत्ति रक्षन का अधिकार

प्रत्येक कम्यून की एक काग्रेस होती है। कम्यून काग्रेस के सदस्या को कम्यून का सदस्या द्वारा अपने मध्य में से निर्वाचित किया जाता है। दैनिक प्रवासन काग्रेस द्वारा निर्वाचित परिषद द्वारा सम्मादित किया जाता है। परिषद का एक अन्यस, कई उपाध्यम एव सदस्यमण होते हैं। कम्यून के सदस्य विभिन्न उत्पादन टूकडिया में विमा जित होते हैं जो उत्पादन, अम्म सगठन एवं लेखा की व्यवस्था करते है। प्रत्येक हीर्मिन (Hanang)—जिम्मतम प्रशासकीय इकाई—की एक कम्यून होती है। कम्यून म सामृद्धिक भीजनातम होता है एवं दिनया की घरा पर भोजन बनाने के काय में मुक्ति प्राप्त हो गयी है।

वाकिस्तान में बुनियादी लीकतात्र

8 अक्टूबर, 1958 ई को पाकिस्तान में लोकन न के अक्षफल होन पर तरकालीन राष्ट्रपति इस्क दर पिजा ने सिवधान को अप करत हुए सकट कात की पोपणा की भी एवं सैनिन कानून सामू कर दिया था तथा जनवरत समुख्यां को मार्गल तो असासक निमुक्त किया था। 20 अक्टूबर, 1958 ई को पानिस्तान में पुत सितक कालित हुई। अपूबसा ने इस्क दर मिजी को अपस्य करके पानिस्तान के राज्याख्या का पद प्रकृण निया। इस प्रकार पाकिस्तान में सिन्छ तानासाही स्थापित हो गयी थी। पदाख्य होन पर जनरस अपूज ने सीम्म हो ने बम्न के लावतान के संस्थापना के बन्त दिया था। 1959 ई म अपूज ने सीम्म हो गयी बम्न के लावतान के संस्थापना की अनुसार दिसम्बर 1959 एवं जनवरी 1960 ई न

निर्वाचन हुए। इसके पूर्व पाकिस्तान में स्थानीय शासन के अत्तगत ब्रिटिशकालीन संस्थाएँ—नगरपालिकाएँ एवं ग्रामीण क्षेत्र में जिला बोड—कायम थे।

प्रस्तावित बुनियादी लोकत न के अनुसार प्रशासन को पाच स्तरा---प्राग्तीय, क्षेत्रीय, जिला, यांना एव तहसील तथा यूनियन (गाव एव शहर)---मे विमाजित किया गाया था तथा इन सभी स्तरो पर बुनियादी लोकत त्रीय सस्याओं की स्थापना की गायी था। सबसे नोले ग्राग एव नगर स्तर पर कमश यूनियन काल सल एव टाउन कमेटियाँ स्थापित की गयी। यह बुनियादी लोकतान की प्रारम्भिक इकाइया थी। ग्राम, नगर, पाना, तहसील एव जिला स्तरीय सस्याओं को बुनियादी लोकतानिक सस्याओं (Basic Democratic Institution) की सन्ता दो गयी और इन सस्याओं के सदस्यों को बीसिक डेमोन्टेस (Basic Democrats) कहा गया।

यूनियन काउन्सल एव टाउन कमेटी

इनका निवांचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता था। सरकारी कमचारी इनका सदस्य नहीं हो सकता। प्रामीण क्षेत्र को सस्या को यूनियन काउ सल एव शहरी क्षेत्र की सस्या को टाउन कमेटी की सजा दी गयी। अल्यसक्यका एवं हिन्यां को निवांचन से उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त न होने पर उस वय के सदस्यों के मनोनीत किये जाने की व्यवस्था थी। वो प्रकार के सदस्य होते थे—निवांचित एवं नियुक्त या मनोनीत। कृषि, उद्योग, सामुदायिक निर्माण, नलकूप, तालाय, जल व्यवस्था, अन्न का उत्थादन, सावजनिक मार्गी एवं सडका का निर्माण एवं निरीक्षण, किष्मवां, गरीबों की सहायता, स्वास्थ्य सुरक्षा, विक्षा, येवे आदि इन सस्याओं के काय थे।

थाना एव तहसील काउन्सल

क्षेत्र की धूनियन परिपदो एक टाउन कमेटिया के अध्यक्ष इनके पदेन सदस्य होते य । इसके अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा कुछ सदस्य मनोनीत भी किये जाते थे। मनोनीत सदस्यों की सक्या निर्वाचित बदस्या की सस्या के आधे से अधिक नहीं होती थी। भाना या तहसील की परिपदों ना अध्यक्ष परगनाधीश होता था। इसका काय यूनियन परिपदा के कार्यों ज समज्य करना था। शासन एव जिला परिपद द्वारा इन परिपदों को अप काय भी सीपे जा सकते थे। इन प्रदत्त नार्यों के लिए ये परिपदें जिला परिपदा के अदि उत्तरदायों होती थी।

जिला परिपद

जिला परिषद (District Council) म पदेन एव नियुक्त सदस्य होते थे। याना एव तहसील परिषदा, नगरपालिकामा के अध्यक्ष एव के दूनगण्ड बोड क उपाय्यक्ष जिला परिषद के पदेन सदस्य होते थे। इसके अविरिक्त के द्वीय सत्तार का विनिन्न विमागा के प्रतिनिधिया के नाम सदस्यता के लिए प्रसाविक कर का आधिकार होता या। य सदस्य कमिस्तर द्वारा नियुक्त किये जात थे। जिलायोदा परिषद का पदन

सदस्य एव अध्यक्ष होता था। जिला परिपर्दे महत्वपूण विकास याजनाएँ प्रस्तावित बरती थी। इसके अतिरिक्त व जिला की स्थानीय समस्याओ एव सामा य विकास स्थानीय शासन | 1001 योजनाओ पर विचार नरती एव सुभाव दती थी। सावजनिक मागी का सरक्षण, वाचनालय, चिनित्सालय मावजनिक वगीचा, नेल व मदाना, सराया, सफाई एव स्वास्त्व सहवारिता आ दोलन का विकास, ग्राम-उद्योग प्राइमरी ल्लूल आदि की व्यवस्था जिला परिषद के ही वाजित्व थे। शिक्षा, सन्कृति, सामाजित एव आणिक कत्याण परिषदा व वैकल्पिक काय थे।

इसक अतिरिक्त क्षेत्रीय एव प्रा तीय विकास परामग्रदायी परिपद होती थी। होत्रीय परिपदा म भी पनेन एव नियुक्त सदस्य होते थ । कमिवनर इसका अध्यक्ष होता था। यह महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विकास योजनामा पर विचार करती थी। विकास परामद्धवायो परिपदा न सदस्या को राष्ट्रपति द्वारा निष्ठुक्त किया जाता था । हनम पदन सदस्य भी होत थे। यह परिषर्वे स्थानीय परिपर्वो एव प्राप्त के अस्य स्थानीय अधिकारिया क कार्यों क सम्बाध म परामश देती थी। विभिन्न परिपदा के कार्यों म सम वय, परिपना एवं अयं अधिकारिया को अनुवान देने वादि विषयों के सम्बंध म विकास परिवर्द परामश्च प्रदान करती थी। इन समस्त परिपदी का कायकाल 5 वप था। बुनियादी लोकत न का कायकाल बहुत कम रहा था। बुनियादी लोकत न के समयका न इसे पाकिस्तान व निए सर्वोत्तम शासन व्यवस्था की सजा की थी। इसने पानिस्तान म ब्याप्त राजनीतिक श्रष्टाचार एव अराजकता हे जनता की रक्षा की थी, सत्ता का विके द्रीकरण किया या एवं नागरिकों को शासन की विभिन्न सस्याओं म योग्वतानुसार माग सन का अवसर प्रदान किया था। इससे जनता म राजनीतिक चैतना का प्रसार हुआ था तथा जनता व विमिन वर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इतक अतिरिक्त गृह व्यवस्था सरल, कम खर्वाली, स्पायी एव हेंढ शासन प्रवान करने म सफल हुई थी।

' इर ... लेक्नि इनक आलोचको का यत इसस मित हैं। उनके अनुसार यह व्यवस्था अलोकता ित्रक थी। इसकी आत्मा अधिनायकवादी थी। एक अधिनायक मे और आसा मी क्या हो सकती थी। इसक द्वारा लोकत न का गला घोटा गया था। यह व्यवस्था शासन म जी हजूरी को मर्ती करन का एक साथन थी। निर्वाचित एव प्रत्यक्ष मत दान को उपेक्षा को गयी थी। पाकिस्तान म यह व्यवस्था वसफल रही और अस्यायी सिंख हुई थी। 24 माच, 1969 ई को अगूव के पतन के साथ इस व्यवस्था का मी अत ही गया था।

राजनीतिक दल द्विदलीय एव एकदलीय पद्धति [POLITICAL PARTIES (I)]

राजनीतिक वल आधुनिक राजनीतिक जीवन की मुख्य विशेषता है। लोक त तीय प्रणाली की सफलता ने लिए दलो का अस्तित्व अनिवाय एवं आवश्यक है। इसके अमाव में लोकतन्त्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अत वतमान गुग में वल एवं लोकत न एक दूसरे के पूरक बन यथे हैं। प्राय समी लोकत तीय देशा के सगठना से राजनीतिक वल अमित कप में सम्बन्धित हैं। लोकत प्रीय देशों में ही नहीं निरकुशतन्त्री एवं अधिनायकत जी देशों में मी दलीय प्रणाली अनिवाय हो। गयी है। ब्राइस के अनुसार "राजनीतिक वल अमित में हैं। विशेषतंत्र में एवं नहीं हैं। जिसमें वल न हो और न कोई व्यक्ति यह बता सकता है कि लोकत तीय शासन का जनके अमाव में सचालन किस प्रकार सम्मव है।" मुनरों के अनुसार "लोकता प्रकार सम्मव का सुसरा नाम राजनीतिक दलो हारा सासन है। राजनीतिक वलो के अमाव में कही स्वत न शासन नहीं रहा है।" विशेष लोकता तीय आसहारिक वलो का सोकता निर्माण सामन नहीं रहा है।" के अनुसार "राजनीतिक वलो हारा सासन है। द्वारोप स्वत्व के अनुसार "राजनीतिक वलो हारा सासन है। इसे अनुसार "राजनीतिक वलो हो। सोकता निर्माण सोकता निर्माण से अमाव में सामन नहीं रहा है।" विशेष सोकता निर्माण से अमाव में कही स्वत न शासन नहीं रहा है।" असे अमाव में सामन नहीं नहीं सोकता निर्माण सामन नीय अवस्था से कोई विरोध नहीं है अपितु वे ही। उसे अवस्था हो कोई विरोध नहीं है अपितु वे ही। उसे अवस्थाहारिक वनाति है।"

^{1 &#}x27;Parties are mevitable No free country has been without them No one has shown how representative government could be worked without them '-Bryce Modern Democracies, Vol I, 1929, p. 134

^{2 &}quot;Government by free political parties is merely another name for democratic government No where has there ever been a free government without political parties "—Munro The Govern ment of the United States, 1947, p. 113

³ Far from being in conflict with the democratic government, it is the only thing which renders the later feasible '—Stephen Leacock Elements of Polistical Science, 1933, p. 313

दलो की परिभाषा

राजनीतिक दलों की विभिन्न विद्वानों ने भिन्न मिन परिमापाएँ दी हैं। एडमण्ड बक के अनुसार "राजनीतिक दल ऐसे मनुष्यों का समूह है जो उन सिद्धान्ता के आधार पर जिनके सम्बाध में वे सहमत हो अपने सामूहिक प्रयत्नो द्वारा राष्ट्रीय हित के सबद्ध न हेतु एक सूत्र म आवद्ध होते है। "अ बक ने अपनी परिमापा म तीन तत्वो—मनुष्यो के समूह, सामान्य स्वीकृत सिद्धा तो एव राष्ट्राय हित के सवधन—पर वत दिया है। इनमे से किसी एक तत्व के अमाव मे किसी मानव समूह को बल की सना मही दो जा सकतो है। उदाहरण के लिए वर्गीय एवं साम्प्रदायिक दस इस परिमाया ेहे अनुसार दल की श्रेणी मं नहीं आ सकते। मारत का साम्यवादी दल, अकाली दल, पुरितम तीय एव हिंदू महासमा वर्गीय एव साम्प्रवायिक दल हैं। साथ ही साथ वे उप्पान पर पूर्व है । देश की दल की परिमापा के अनुसार इन दलों को दल नहीं माना जा सकता । वक की परिचाषा का यह दीव है। एक अप दीव यह है कि वक ने यह स्पष्ट रूप में उल्लेख नहीं किया है कि राजनीतिक दल राज्य शक्ति पर अधि कार करके अपने जद्देश्या की प्रास्ति के लिए प्रयत्न करता है। लीकाँक के अनुसार राजनीतिक दल से अभिप्राय नागरिका के उस यूनाधिक सम्बद्धित सम्रह से है जो एक "राजनीतिक इकाई के रूप न काय करते है। तावजनिक प्रक्तो पर वे समान विचारी की मानत एव स्वीकार करते हैं तथा सामा य उद्देश की पूर्ति के लिए अतदान राक्ति हारा शासन पर अपना अधिपत्य स्थापित करना वाहते हैं।"⁵ गिलकाइस्ट के अनुसार राजनीतिक दल "नागरिकों के उस संगठित समूह को कहत ह जो राजनीतिक हस्टि से प्रमान विचारा के हा तथा जो एक राजनीतिक इकाई के रूप म काय करके धासन पर अधिकार करने क इच्छुक हो। " सकाइबर के अनुसार राजनीतिक दल ' वह मानव-समुदाय है जो किसी सिद्धा त या नीति को सगढित होकर सबधानिक दग से धासन

^{4 &}quot;A political party III a body of men, united for the purpose of promoting by their joint endeavours the public interests upon same polincal principles on which they are all agreed - Edmund Burke quoted by M G Gupta Modern Governments Theory & Practice 1967, p 126

By a political party we mean a more or less organized group of citizens who act together as a political unit. They share or Profess to share the same opinion on public questions and by rectrising their voting power towards a common end, seek to obtain control of the government —Stephen Leacock Ele ments of Political Science op cil, p 311

^{&#}x27;A political party may thus be defined as one organized group of citizens who profess to share the same political views and who by acting as a political unit try to control the governmen Gilchrist Principles of Political Science, 1930, p 327

1004 अधिनिक शासनत न

का आधार बनाने का इच्छुक हो।" मेटिल के अनुसार "राजनीतिक दल नागरिको का वह समूह है जो यूनाधिक रूप से समठित हो एव जो राजनीतिक इकाई के रूप म काय करके मतदान शक्ति द्वारा अपनी सामा य नीतिया के किया वयन हेतु शासन पर अधिकार करने के लिए प्रयत्नशील हो।"

डॉ आर्जीवादम के बनुसार "राजनीतिक दल से अय व्यक्तिया के उस सगठित निकाय से है जो देश के राजनीतिक जीवन म कुछ सिद्धा तो एव नीतिया को मानते हैं तथा उनका पालन करके समग्र रूप मे देश हित के सवर्द्धन के इन्छक होते हैं।" किसी राजनीतिक दल की नीति या कायत्रम यदि सुस्पष्ट नहीं हैं तो उसे दल नहीं माना जाना चाहिए। दल एव समूह (group) या गुट (faction) म अत्तर है। इसी प्रकार दल के नेताओं के मध्य वैचारिक मतभेदों को व्यक्तिगत विवाद की सन्ना नहीं दी जानी चाहिए। अत राजनीतिक दल के तीन प्रधान तत्व हैं (1) सगठित मानव समुदाय, (2) नीति एव सिद्धा त की एकरूपता, तथा (3) देश या वग-समुदाय मा बग विशेष के हित का सबद्ध न । यदि दला की कायपद्धति को अनिवायत लोक-ता निक रीति तक सीमित कर दिया जाता है तो का तिकारी दला की दल नहीं माना जा सकता । अत ऐसी परिमापा व्यावहारिक नहीं है । इसी प्रकार देश हित को ही यदि राजनीतिक दल का उद्देश्य मान लिया जाता है तो वर्शीय एव साम्प्रदायिक दलो को दल की सज़ानहीं दी जा सकती। इस प्रकार के दला को स्थान देने के लिए दल की परिमापा पर्याप्त ब्यापक होनी चाहिए । इस दिट से दल स्वीकृत एवं सुस्पष्ट सिद्धाता एव विचारा के आधार पर निश्चित राजनीतिक या सामाजिक सध्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नक्षील समान विचारा वाले व्यक्तियों का एक एसा समूह है जिसका अपना सगठन एव निश्चित कायनम होता है तथा जो सक्ष्य की पूर्ति हेत् शासन पर नियापण कर इच्छक होता है। राजनीतिक दलो के हित राष्ट्रीय एव उनके तरीके सबैधानिक हो सकते है। लेकिन ऐसा होना अनिवाय नहीं है। लोकता निक देशों म

[&]quot;A political party is an association organised in support of some principle or policy which by constitutional means it endeavours to make the determinent of government -- MacIver Modern State, p 396

[&]quot;A political party consists of a group of citizens more or less organised who act as a political unit and who by the use of their voting power, aim to control the government and carry out their general policies —Gettell Political Science 1956 p 289

[&]quot;By a political party we mean an organised body of people who stand for certain principles and policies in the political life of the country, by whose operation they seek to promote the interests of the country as a whole -Asirvatham op cit, 1965, p 422



1006 | आधुनिक शासनत त्र

जनता को वास्तविकता को समफ्रने में सहायता प्राप्त होती है। सर्विन के अनुसार दल "विचारों के दलाल हैं।" अशोंबादम के राज्यों में दल 'लोकत'न के आधार सामा य इच्छा' के निर्माण एवं विकास को सम्मव बनाते हैं। उजनीतिक दला के फलस्वरूप जनता सर्वेव सुजग एवं जागरूक रहती है।

(5) दला के कारण मतदाताओं को मतदान में बढ़ी मुविधा रहती हैं। निर्माचनों में दलो द्वारा अपने प्रत्याक्षी खढ़े किये जाते हैं। मतदाताओं को प्रत्याक्षिया के ब्यक्तिगत विचारा को जानमें की आवश्यकता नहीं होती। जनता दल को मत देती हैं। दलों के द्वारा ही सामा य ब्यक्ति की तरफ से सावजनिक प्रश्नों पर विचार विमधं किया जाता है।

(6) दलीय अनुदासन विधानमण्डल के सदस्यां की स्वार्यी इच्छाओं और भ्रष्टाचार पर प्रतिवाध का काय करता है ¹⁶ तथा दलीय सदस्यों मे टीम मावना एव सहयोगपूबक काय करने की प्रवृत्ति का सूत्रपात करता है।

(7) दलीय व्यवस्था लोकता निक शासनो की निरकुराता पर प्रतिव घ है। इसके फलस्वरूप शासन म सभी क्षेत्रों एव हितों का प्रतिनिधित्व सम्भव हो जाता है। यह शासन को अनुत्तरदायों होने से रोकती है एव उसकी जटिलता को कम करती है। सकाइवर के शब्दा में दलीय पह ति के कारण वर्गीय राज्य ने परिवर्तित हो जाता है। इसका यह ति के कारण वर्गीय राज्य ने परिवर्तित हो जाता है। इसका यह थय है कि दलीय व्यवस्था के विकास के फलवरूप शासन का सवासन किसी वग विशेष के हित की बजाय सम्भूण देश के हित में होने लगा है तथा हिंसासक परिवतनों के स्थान पर सबैधानिक तरीका से शासन में परिवतन सम्भव हो सके हैं।

बेजहाँद के राज्यों में दलीय शासन ससदीय शासन का मुख्य सिद्धानत है। 16 काइनर के अनुसार 'दल रिहासन के गीछे की शक्त हैं एवं राजनीति का केद्र है। 18 वह ही राजा है। 17 राजनीतिक वल गृह गुद्ध पर प्रतिव च लगाने वाली सेना है। वली हारा व्यक्ति में सिर्फ सेर को पालत बनाया जाता है ने बहुका के समय के

स्थान पर मता के समय की जाम देत है, हिंसात्मक कार्ति के स्थान पर वे शासन में

¹² The parties are the brokers of ideas'—Lowell op cit, cited by

¹³ Asırvatham op cit, p 424

¹⁴ Ibid , p 136

^{15 &#}x27;Party government is the vital principle of representative government —Bagehot, cited by Lasks Parliamentary Government in England, op. cit., p. 71

Political parties are the power behind the throne', 'the center of political gravity —Cited by M G Gupta op at, p 136

¹⁷ Party II King' -Ibid , p 274

राजनीतिक दल द्विदलीय एव एकदलीय पद्वति | 100 चान्तिपुनक परिवतन के लिए माग प्रशस्त करते हैं। ¹⁰ वे बहुमत के अत्याचार व विरुद्ध समय करते हैं, उसे समत आचरण के लिए मेरित करते हैं। अल्पसरमकों की विद्धात के निषय को इस थाशा के साथ स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने है कि समाज म परिवतन होते ही रहते हैं। दल शासन को स्थामित एवं सुहबता मवान करते है।

; -

द्वीय व्यवस्या की वीव वासोचना की गयी है जो निम्नवत है (1) बला के फलस्वरूप उनक सदस्यों का व्यक्तित्व नव्ट ही जाता है। जिल षाइस्ट 10 के अनुसार ने देश के राजनीतिक जीवन को य त्रवत एवं कृतिम बना देते हैं। विरोधी दल द्वारा सदव ही सत्तारूढ दल की बालोचना की जाती है। द्विदलीय पढ़ित म यह दोप अत्यधिक युत्तर होता है। कठोर दलीय अनुपासन एव मुहढ सगठन के कारण तदस्यों के व्यक्तित्व का हनन होता है। दलीय शासन के लिए दलीय एकता वनिवाय है व्यत विधानमण्डलो म स्वतः त्र सवस्या के लिए कोई स्थान नहीं होता। इलीम धासन में अयोग्य व्यक्तियों का अधिकार ही जाता है।

(2) दलगत स्वाय और हित प्रमुख होते हैं एव व्यक्ति के द्वारा दलीय हिन्द कोण से सोचना प्रारम्भ कर दिया जाता है। क्षेत्रीय एव साम्प्रवायिक हितो के समक्ष राष्ट्रीय दित गोण हो जाते हैं। राष्ट्रीय मक्ति के मूल्य पर दलीय मक्ति विकसित होती है। 20

- (3) राजनीतिक दल हर मकार से सत्तारूड रहने का प्रयत्न करते हैं फल-स्वरूप ब्लीय नेताओ द्वारा कुल्वित भावनाओं को उमारने का प्रयत्न किया जाता है। ईमानदारी समाप्त हो जाती है तथा साम्प्रदायिक एव वगगत वैमनस्य उमारे जाते हैं।
- (4) जन समयन प्राप्त करने के लिए दला के द्वारा जनता की लुशामद की णाती है और मत प्राप्ति हेतु विभिन्न लोकप्रिय विधिया का निर्माण किया जाता हैं। गिलकाइस्ट के अनुसार इस प्रकार की विधियों सामा यत अवैज्ञानिक एव चुरी होती हैं।22
- (5) जनता के मत प्राप्त करने के लिए दलो द्वारा जनता को हर प्रकार से विकत्ताया जाता है। मतवातामा को रिक्वत दी जाती है, उनकी खुवामद की जाती है, उ हैं फ़ुसलाया जाता है ।²² जनता में इससे मतभेद, कट्ता, पुणा एवं हेप फैनता है ।

¹⁸ A political party is an army that prevents civil, war political sham sham sham sham sham battle of os ponticat party is an army that prevents civit, was pontical tame the tiger in the men they "replace the bullets by one of ballot — M G Gupta op cii, p 136 battle of 19 20 21 22

tota p 331 'Voters are bribed, flattered and cayoled "—Astrvatham of ct.,

दला द्वारा बरोमनीय भाषा म यलत तर्क प्रस्तुत किय जाते हैं। बाइस के अनुसार दल राष्ट्र को दो विरोधी पक्षो म विमाजित कर देते हैं जिसस मनुष्यो म पदापात पर कर जाता है और एक पक्ष दूसरे पक्ष को सादेह की इंग्टि से देवने सगता है। प्रतिनिधि दलीय अनुसासन के कारण मुलाम बन जाते है तथा स्वता म विचार एव उनकी अमि व्यक्ति समाप्त हो जाती है।

(6) दलीय व्यवस्था राजनीतिक जीवन म भ्रम्टाचार को जम देती है । 19वी सदी मे अमरिकी राजनीतिक जीवन म व्याप्त लूट प्रवा इसना प्रमाण है। मधि संपुक्त राज्य अमिका म इसका प्रमाव कम तो हुआ है परन्तु अमिका तथा अप देशा जो फांस, कनाडा एव आस्ट्रेलिया म यह आज भी कायम है। ¹³ मारत आदि देशों म दलीय व्यक्तिया को सत्ताव्ड इस हारा अनेक महत्वपूष पदा पर नियुक्त किया जाता है।

ब्राइस ने दलीय व्यवस्था के दोयों को समीक्षा करते हुए कहा है कि इसके कारण ससद समाम-स्थली वन जाती है। दल जाते एव बात रहत हैं, राष्ट्रीय हिंस जनके द्वारा मुला दिये जाते हैं, निष्ट्रियता (hollowness) एव कर्तव्यक्षीतरा को वेदा यहा मुला दिये जाते हैं, निष्ट्रियता (hollowness) एव कर्तव्यक्षीतरा कर देते हैं तथा समस्याका पर निष्पक्ष हिंद्ध स विवार असम्मव हो जाता है। दलीय पढ़ित के कारण प्रतिनिधि दास बन गये हैं, स्वतन्य चितन को प्रथम नहीं दिया जाता है राष्ट्रीय विवारण स्थानीय क्षेत्रत जाता है, सावजनिक पदो पर दलीय व्यक्तिया की निष्पुधितयों की जाती हैं समाप्त का निवक स्वर गिर जाता है, समी प्रश्नाप र दलीय हिन्दियों से जाती हैं। समाप्त ना नत्त करते गिर जाता है, समी प्रश्नाप र दलीय हिन्दियों से विचार किया जान तत्तवा है। कि विवार के सिए आतोचना की जाती हैं। दलीय नेताओं का देव के राजनीतिक एव सामाजिक जीवन पर नियायण स्थापित हो जाता है। बाइस का कथन है कि "दलीय प्रावना के कुछत्या से इतिहाल मरा पका है।" समग्रवादी देवों म दल एव तासन प्रकार हो जात हैं। वोक्त प्रति से स्थापित प्रकार हो जात हैं। वोक्त प्रति से स्थापित प्रकार हो जाता है। सोक्त नीय देतों से भी दलीय निरक्ताता जाता है।

लिक्त इन दापों के होते हुए भी वतमान नाकत तो मे दल एक अनिवायता है। अनेक बुराइयो की वे दूर भी करते है। उनके अभाव म लोकत न प्राय असम्मय है। दनों को लोकत न नी आधारशिला कहा जा सकता है। अधिनायकवादी देशों में भी दलीय व्यवस्था ही धासन का आधार होती है। इटली में मुसोतिनी ने फासी दल

²³ Bryce op af , p 131

²⁴ Bryce Ibid , p 132

²⁵ Bryce Ibid, pp 130 133

हिटलर न जमनी म नाजी दल, का निर्माण किया था। पानिस्तान म भी जरतत अपूज को अन्तरोगस्या समयन दल वा निर्माण करना पदा था। अंत दलीय व्यवस्था आधुनिक सासन-ध्यवस्था वा एव अनियाय तत्व है।

दल-विहीन लोफतन्त्रीय व्यवस्था

दल निहीन लागरा प्रश्नी आज बहुत चर्चा है। सर्वोदयी विचारक निदलीय सामसे प्रस् में समयेक हैं। सिवन यह उनवा कोइ योलिक विचार नहीं है। कसी का बस्तर पा ति जिस समाज म दर्ता ना अस्तिरत होता है वहाँ सामा य इच्छा की ठीक अभिष्यक्ति सम्मन नहीं है। अमरिकी सिविधान निर्माग दलीय व्यवस्था के विवद्ध ये। राष्ट्रपति वाधिगटन दक्षीय व्यवस्था का विवद्ध ये। राष्ट्रपति वाधिगटन दक्षीय व्यवस्था का विवद्ध समाराह स अमरिकी साव पात म हतीय अवस्था को जोई स्वान नहीं दिया गया था। वाधिगटन ने अपने विदाह समाराह स अमरिका म इंदिनीय व्यवस्था के विवद्ध वेतावनी दी थी। दलीय मानना प्रतिहिता उत्पात करती है एव मयानक प्रकार को निरकुराता की स्थापना करती है। अस्तर्या के विदार स्थापना करती है। क्षेत्र मंत्र वेतावनी विचार स्थापना करती है। क्षेत्र स्थापना क्षेत्र स्थापना है। क्षेत्र स्थापना करता को क्षेत्र स्थापना को करता को विवद्ध स्थापना करता को करता को वे व्यवस्था के अस्तर स्थापना को विवद्ध स्थापना के असुसार सारतीय लोकता न को विवद त्या है। अस्तरकाश्ची दिसीय राजनीवि के तीक कालीचक है।

लिन दल विहीन लायत य एक कल्पना है और अयावदारिक है। दलविहीन लोयत म गाहर से जितना ही आक्षपन नयो न हो पर तु इसकी वाद्यतीयता
स्पावहारिक्ता की प्रयोगि पर लारी नहीं उतरती। इसके अतिरिक्त नमी देशा म
स्व स्थायी रूप थारण कर चुने हैं। मुस्य प्रक्त यह है कि इति का उप्तरण कर चुने हैं। मुस्य प्रक्त यह है कि इति सा उपारण कर चुने हैं। मुस्य प्रक्त यह है कि इति स्व स्थान का उप्तरण कर करने के लिए कोई तियम बनाता सम्मव है ?
यदि योई तियम बना भी दिवा प्या तो क्या वह क्यांचित हो सकेगा? बया सक्ताकड दल इस प्रकार की विधि को सायता देशा ? यदि नहीं, तो दलीय व्यवस्था
भी जपनी उपयोगिता स्वय गिद्ध है। बाइस के अनुसार दलीय व्यवस्था द्वारा अनेक
मुराइया का दूर किया जाता है। दल विहीन लोकत ना प जन शिक्षा का एकमाम
तरीका स्वत म सदस्या के विचार, भाषण या तेत हा। वा तन के अमाव म विधान
पण्डल के सदस्या प मर्तन्य की स्थापना नहीं हो सनेथी। शासन के उत्तरशायिक का
निर्पारण सम्मव न हो सनेथा। और न शासन के विधिन अयो म एकता स्थापित करता

²⁶ A Appadoras The Substance of Politics, 1961 p 413

²⁷ V P Verma Modern Indian Political Thought, 1964, pp 554

ही सम्भव होगा। ब्राइस का कथन है कि अभी तक कोई यह नही बता सका है कि दलों के अमाद म शासन कसे चलेगा । पील, डिजरेली एवं ग्लैडस्टेन जैसे राजनीतिज्ञ दलीय व्यवस्था के दोषा से परिचित होते हुए भी उसके महत्व को स्वीकार करते थे। ²⁸ डॉ आशीर्वादम के अनुसार सभी विघायक विवेक के स्रोत अथवा प्रकाश-स्तम्म नहीं होते । दल उनमें से बहुता का मायदशन करता है । विधायक प्रत्येक समस्या पर विचार के फफट से बच जाते है। उनमे इसकी सहज प्रतिमा भी नहीं होती। मारत जैसे देशों में यदि दलों को समाप्त कर दिया जाय तो निर्देशीय एवं स्वतान सदस्यों के परिणामस्वरूप राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त हो जायेगी । प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वामी होगा । यदि अत्यधिक शक्ति का के द्रीकरण युरा है तो अनावश्यक व्यक्तिवादी यक्तिका विकेदीकरण भी बुराहै। इस आरोप के प्रत्युत्तर में कि दलीय प्रणाली अधि नायकवाद को ज म देती है, हमारा यह कयन है कि अधिनायकवाद सवधानिकत न के अधीन सिक्य सुसगठित दलीय प्रणाली का परिणाम नहीं होता है। दलीय प्रणाली मे विघटन एवं कमजोर होने पर फासीवादी इटली एवं नाजीवादी जमनी की भाति अधिनायकवाद का उदय हो जाता है । यदि दलीय संगठन एवं सम्पत्ति को विधि के द्वारा नियत्रित एव सीमित तथा समाप्त भी कर दिया जाय तो भी दल किसी न किसी वसरे अवाछनीय रूप म उमरेंगे। ऐसी स्थिति म अवैध गुटा के रूप म दल अपने को सगठित कर लेंगे और अपने स्वायों की प्राप्त के लिए हर तरीके का प्रयोग करेंगे। स्मरणीय है कि स्विटजरलण्ड स दलीय भावना का वहत कम विकास हजा है। वहा भा दलीय व्यवस्था को और अधिक इद बनाने की सामाजिक प्रवृत्ति सिक्रय है।

दलीय यवस्या चूिक बाछुनीय एव अनिवार्य है अत उसको स्वीकारना एव मा यता देना कही अधिक उचित है। अध्यादोराई का यत है कि दलीय अपटा चार के उन्मूलन के लिए कठोर विधियों का निर्माण किया जाना चाहिए। सिन्ध्य सावजिनक संवा भाव से ओतग्रोत व्यक्तियों को राजनीति म अधिक माग लेने के अयसर दिये जाने चाहिए व्यवस्थापिकाओं में दलीय अनुवासन को शिषिल किया जाना चाहिए तया सदस्यों को स्वतन्त्र मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए। देश को व्यवस्थित रखन के लिए अनता को अतिवादों आ दोलना से यचना चाहिए तथा किसी दल के प्रति स्थायों मेंकि नहीं रखनी चाहिए। दूसरे छन्दों म, जनमत को सदय गतिशील होना चाहिए। 200

दला के सफलतापुर्वक बाय करने के लिए अग्र परिस्थितियाँ आवश्यक हैं "

²⁸ Bryce op at, p 138

²⁹ Asırvatham op cut, pp 425 26

³⁰ Appadoras of cst pp 483 484

³¹ Based on Dr E Asirvatham op cit, pp 426-28

- (1) बहुदनीय पद्धित को अपेक्षा सुदृढ दिवलीय पद्धित का निकास किया जाना चाहिए । द्विवनीय पद्धित के अत्वयत उत्तरदायित्व का निधारण एव स्थायी वकत्विक सरकार का निर्माण सरलतापुवक सम्मव होता है । एक्टलीय व्यवस्था अधिनायक वादी व्यवस्था है ।
- (2) स्वार्थी एव निश्चित काग्रकम तथा नीतियां के अयाव म दलों के सगठन पर प्रतिवन्य होना चाहिए। असहिष्णु तथा अधिनायकवादी दलों के प्रति कोई उदा-रता नहीं दिखायी जानी चाहिए।

(3) जाति, वग एव धम पर आधारित दलो का देश की राजनीति मे स्थायी

स्थान नहीं हाना चाहिए। ऐसे दल राष्ट्रीयता के लिए खतरा होते हैं।

(4) दला की निजी सैनिक टुंकडियाँ नहीं होनी चाहिए क्यांकि दलीय सिनिक टुंकडियाँ अपने प्रदेशनों से मतदालाओं को प्रमालित तथा मयमीत करती रहती हैं और जवैद्यानिक तरीको का इनके द्वारा प्रयोग किया जाता है।

(5) दलीय आधार पर शासन के अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की जानी

चाहिए।

(6) योग्य, निप्पल तथा निमल चरित्र के व्यक्तियो को ही दलीय नेतृत्व सीपा जाना चाहिए तथा दल के नेताका और उनके गुट को तानाखाही नहां स्थापित होने देनी चाहिए।

(7) मतदाताओं को प्रबुद्ध, शिक्षित, विवकी एव निषय बुद्धि से पुक्त होना चाहिए। यदि देश को सामा व चरित्र तथा नेताना का व्यक्तित्व और चरित्र उच्च श्रेणी का तथा निर्दोष नही है, ता दलीय व्यवस्था की असफलता निश्चित है।

(8) देश में स्वत न, निर्भोक एवं मुविश समाचार पन (प्रेस) दलीय अधि-

नायकत्व के विरुद्ध रक्षा-कवच के रूप म काम करते है।

वलो के प्रकार

मिलकाइस्ट के अनुसार दक्षा के जार सामा य प्रकार होते हैं (1) जपनादी (Radicals) (2) प्रतिक्रियानादी (Reactionaties), (3) उदारनादी (Liberals), एवं (4) अनुदारनादी (Conservatives) । उपनादी समान की गतमान स्थिति एवं व्यवस्था में आमृतन्त्रुल परिनदान के पदापाती होते हैं। इसके विष रित, प्रतिक्रियानादी इस प्राचीन व्यवस्था एवं परम्परा के समयक व पदापाती हैं। यह दोनों म्यितियाँ अतिनादी हैं। उदारनादी इस नं वर्तमान सस्थाओं के परिवात का नं परिवात का की पदापाती हैं तथा अनुदारनादी इस नं वर्तमान सस्थाओं के अनुरक्षण के समयक होते हैं। विकार के एक्षापाती हैं तथा अनुदारनादी इस नं वर्तमान सस्थाओं के अनुरक्षण के समयक होते हैं। विकार ये चारो प्रकार के दल एक दूसरे का अतिनमाण करते हैं और सम्भव हैं कि एक ही दल में चारो प्रकार के दल एक दूसरे का अतिनमण करते हैं और सम्भव हैं कि एक ही दल में चारो प्रकार के दल एक दूसरे का अतिनमण करते हैं और सम्भव हैं कि एक ही दल में चारो प्रकार के विज्ञा पायं जाते हां। संघीय देशों में वे द्वाप एवं प्राचीम सत्ता के पक्षपाती दल होते हैं। "संच्या की इंग्डिंग ने तीन प्रकार की

³² Gilchrist op est, pp 329 30

दलीय पद्धति होती है एकदलीय, द्विदलीय एव बहुदलीय। एक्दलीय पद्धति अधि नायकवादी एव लोकतः न विरोधी है।

द्विदलीय पद्धति (BI PARTY SYSTEM)

इस पद्धित के व्यापत देश में प्रधानत दो दल होते हैं। प्रेट ब्रिटेन एव समुक्त राज्य अमेरिका द्विदलीय देश हैं। द्विदलीय पद्धित के निम्म गुण हैं (1) सावत अधिक स्थिर एव स्थानीय होने के कारण दीयकालीन नीतिया का निर्माण एव व्यु गमन सम्मद होता है, (2) जन इच्छा को सुस्पष्ट अधिक्यक्ति सम्मद होती है। निर्माण करता है, (3) उत्तर दायित का निर्माण करता है, (3) उत्तर दायित का निर्माण करता है, (3) उत्तर दायित का निर्माण करता है, (4) सस्तीय व्यवस्था प्रधान देशों में द्विदलीय पद्धित में अपनिष्ठ किया जातिक होता है। (4) सस्तीय व्यवस्था प्रधान देशों में द्विदलीय पद्धित में कल दाया मिन्य करता है, (5) वैकलिक सामन के क्या के काय करने के लिए विरोधी दल सदैव उपलब्ध रहता है। दित्रीय पद्धित में विरोधी दल अनुत्तरदायी दश से काय नहीं कर सकता। शासन की आतीका के लिए उसे सत्तत क्य से जायक्क रहना पडता है और शासन की कमकोरियों का पर्दाक्त में विरोधी दल अनुत्तरदायी दश से काय नहीं कर सकता। शासन की आतीका के लिए उसे सत्तत क्य से जायक्क रहना पडता है और शासन की कमकोरियों का पर्दाक्त में शासन की आतीका व्यवस्था में सासन की अत्तोचना कि कसर विरोधी दल की उपस्थित के कर सकता हो। स्वर्तीय क्या स्था में सासन की अति है। सचक्त स्वर्ति में विरोधी दल की उपस्थित के कारण शासन अनुत्तरदायी नही हो। याता और जनता की किताइयों एव आवश्वकताओं के प्रति पुण सच्च पडता है।

बोच-लेकिन द्विदलीय पद्धति में दौप भी हैं (1) व्यवस्पापिका दो मागा म विमाणित हो जाती है। (2) समाज के सभी वर्षों, हितो एव स्वायों की अमिव्यक्ति द्विदलीय व्यवस्था म सम्मव नहीं है। (3) मताधिकार का प्रयोग दो हो दता के मध्य सम्मव होता है। (4) निर्वाचन में बहुमत प्राप्त करने वाले दक का व्यवहार में अधिनायकत्व स्थापित हो जाता है तथा द्वासा के निर्दुद्ध होने की हर सन्मावना रहती है। द्विदलीय व्यवस्था म मित्रमण्डल तानावाहि वग स काय करता है।

प्रमुख द्विदसीय पद्धति वाले देशा—ग्रेट त्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका—

की दलीय व्यवस्था का उल्लेख निम्नाकित है

ग्रेट ब्रिटेन की दलीय पद्धति

ग्रेट ग्रिटेन म दक्षीय व्यवस्या बतीत सं त्रीमन विकास का परिणाम है। 15वीं सदी म नवसटेरियन (Lancstarians) एव यानिस्ट (Yorkists) न समूह थे, 17वीं सदी म स्टूजट राजाओं के काल म राजा एव ससद म सम्प्रमृता के लिए लम्बा सपर्प हुआ या, फ्लस्वरूप दो समूह वन गये थे। राजा के समयकों नो 'केवलियर' (Cata liers) तथा ससद वे समयकों को 'राउण्डहेड' (Roundheads) क नाम सं पुनारा जाता या। परंजु इन्हें राजनीतिन दला की सना नहीं दो जा सनती। चास्स दितीय

के शासन काल (1679 ई) म जेम्स हितीय की उत्तराधिकार से विचत करने के लिए ससद न निष्कासन विधेयक पारित करने का निश्चय किया था। चाल्स हितीय ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए ससद की भग कर दिया था। इस पर विधेयक के समयका ने नवीन ससद को बाहत करने नी प्राथना की । ये आवदक (Petitioners) कहलाये । विराधियो ने आवेदका के इस प्रयत्न का पृणा की हिप्ट से देखा, अत वे आवेदका के विरोधी (Abborrers) कहलाये। 1688 इ की रक्तहीन जाति के पश्चात ही इगलेण्ड म पूणरूपेण राजनीतिक दनो की स्यापना हुई है। विलियम तृतीय के शासन काल में आवेदना (Petitioners) का हिंग (Whigs) एवं उनके विराधियो (Abhorrers) वा टोरी (Tories) वहा जाने लगा। टारी राजा के समधक थे, ह्विंग दल राजा को राक्तियों को सीमित करने का पक्षपाती था। 1832 ई तक दोनो दल इ ही नामो से विस्यात रहे थे। 1832 ई व मुधार अधिनियम के पश्चात होरियों का अनुवार दन (Conservative Party) एवं ह्विय दल को उदारदल (Liberal Party) के नाम से पुकारा जाने लगा । 19वी मदी म जिटिश राजनीति म इ ही दो दला का प्राधा य रहा था । 1899 ई से शम दल (Labour Party) की स्थापना हुई। धीर घीर इसकी राक्ति मे बृद्धि हुई और 1924 ई म प्रथम बार धमदलीय मि वमण्डल का निर्माण हुआ । 1929-31 ई स दितीय, 1945 ई म त्तीय, 1966 इ. म चतुन एव 1974 ई. म पचम वार श्रमिकदलीय मिनमण्डल पदासद हुए ये । बतमान शनाब्दी के तृतीय शतक मे ब्रिटिश द्विदलीय व्यवस्था समान्त सी होती प्रतीत हुई थी। लेकिन उदार दल धीरे घीरे बिटिश राजनीतिक रनमच में तिरोहित हो गया है, फलस्वरूप ब्रिटिश राजनीति म कवल अनुदार एवं श्रम दल ही दी प्रमुख दल हैं। फरवरी 1974 ई क मध्यावधि निवचिनो म कोई दल स्पष्ट बहु मत प्राप्त नहीं कर पाया, फलस्वरूप धमिक दत ने बल्पमस्यक मन्त्रिमण्डल ना निर्माण किया है।35

बिटिश दलीय पद्धित के उपरोक्त ऐतिहासिक विस्तेषण से यह स्पष्ट है कि विट में प्रधानत सदैव ही दा दलों की प्रधानता रही है और वे दश को राजनीति म मिन्न में हैं। 1930 इ का दछक केवल इसका अपवाद है। उद्मुबन्तर (Duverger) क अनुसार ब्रिटेन में दिदलीय पद्धित है। वहा क्षेत्रीय एक्सदस्थीय निवाबनन्त्रात्र है और सर्वीधक सद प्राप्त करने वाल प्रत्याशी को विवयी योपित क्या जाता है। विट प्रकार की स्वाद्धित क्या कारण है। प्राप्त विनिन्न राजनीतिक दला की व्यवहारवाडी मनोवृत्ति भी इसका अप कारण है। प्राप्त विनिन्न राजनीतिक दला को जान देने वाली राष्ट्रीयता, वम एव मायायी समस्यार मी नहीं हैं।

³³ दिनमान, दिल्ली, 10 माच, 1974

³⁴ Duverger Political Parties, p 217

ब्रिटिश राजनीतिक दलो का कार्यक्रम एव सगठन

अनुदार दल (The Conservative Party)

यह दल परम्परावादी है। ब्रिटिश सामाजिक व्यवस्था के आधारभूत सिद्धान्तो तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति और उत्पादन के साधनो पर व्यक्तिगत नियात्रण को उचित एवं अनिवाय मानता है। इस दल द्वारा इन आधारभूत सिद्धाता को अपरिवर्तित किये विना ही आवश्यकतानुसार सुधार करने का प्रयत्न किया गया है। बनुदार दल 19वी सदी के व्यक्तिवादी राजनीतिक एव आर्थिक विचारी म आस्या रखसा है । वे समाजवादी व्यवस्था तथा राज्य द्वारा आर्थिक मामलो के नियापण के विरुद्ध है। यह दल राष्ट्रीयकरण का सामायत विरोधी है परतु इसने कुछेक उद्योगा का-यण, 1927 ई मे बी बी सी (British Broadcasting Corporation) एव 1926 ई मे विद्युत बोड का-राष्ट्रीयकरण किया या। अनुदार दल समाज म वर भेद को प्राकृतिक एव अनिवास मानता है, लेकिन वस भेद को वे क्षमता पर आधारित मानते हैं। वे वग-सम वय, न कि वग भेद म विश्वास करते हैं। राष्ट्रीयता एव साम्राज्यवाद इस दल के मूल मान हैं। यह दल उपनिवेशो की स्वतानता का विरोधी था। लेक्नि इघर कुछ वर्षों से उसने उपनिवेशों को शीधतापुरक स्वत जला प्रदान की है। ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल की स्थापना एव स्थायित्व का वह पक्षपाती है, साथ ही साथ प्रेट व्रिटेन की यरोपीय साफा बाजार की सदस्यता का समयक है। इस दल की प्राचीन शासन व्यवस्था म पुण आस्था है अर्थात राजा, लॉड समा एव ब्रिटेन के स्थापित चच का समयक है। फाइनर के अनुसार "अनुदार दल काउन, राष्ट्रीय एकता, (ब्रिटिश) चन, शक्तिशाली शासकीय वग एव राज्य हस्तक्षेप से स्वतान 'निजी सम्पत्ति' के सिद्धान्ती का समयन करता है।"35 व्यापारी एव उद्योगपति, बैंको एव शराव उद्योग से सम्बर्धित उद्योगपति, कुलीन-वग, पादरी, साम्राज्यवादी, सैनिकवादी एव व्यवसायी अधिकाशत इस दल के सदस्य हैं। श्रमिको का भी कमी-कमी इस दल को समयन प्राप्त होता है। स्त्रियों के मताधिकार के पश्चात दल के समयको की सस्या म वृद्धि हुई है। दल का युवक वग प्रगतिशील नीतियो का समयक है। 1947 ई मे दल द्वारा औद्योगिक घोपणापत्र प्रकाशित किया गया था । दल न इसम के द्रीय नियोजन (Planning) के सिद्धा त को स्वीकारा था। 1951 ई मे अनुदार दल का 'चनाव घापणा-पन निम्न या ब्रिटेन को पून विश्व-नेता के पद पर प्रतिष्ठित करना तथा आधिक पूनरदार करना। दल न सोवियत रूस के साथ मिनतापूण सम्बन्धा की कल्पना की थी। आन्त रिक क्षेत्र म लोहा एव इस्पात के राष्ट्रीयकरण को निरस्त करने, कोयला राष्ट्रीय करण को कायम रखन तथा मविष्य मे राज्य-स्वामित्व पर पूण प्रतिव घ का वचन दिया था। इसके अतिरिक्त लामास पर बतमान कराधान की दरो को संशोधित तथा

³⁵ Finer op at , p 312

एक। पिकार को सीमित करने और प्रतिवय 3 लाख आवास गृहो के निर्माण का वचन दिया था।' उपरोक्त बिवरण स यह स्पष्ट है कि अनुदार दल ने भी परिवर्तित परि-स्थितियों म अपनी नीतियां म परिवतन किये हैं पर तुदल के मूल सिद्धाता में सहज ही कोई परिवतन नहीं हुए है। अत अनुदार दल भी सुघारवादी है पर तु वह सजगता से कदम उठाता है।

सगठन-अनुदार दल दलीय नेता के चारो तरफ केद्रित होता है। एक बार जो दल कानेतानिर्वाचित हो जाताहै वह आजीवन इस पद पर बना रहता है। दलीय नेता को व्यापक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। सगठन के अध्यक्ष को उसी के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अपनी इच्छानुसार वह अपने पद से त्यागपत्र प्रस्तुत कर सकता है तथा अपने उत्तराधिकारी को वह स्वयं भनोनीत करता है। दल की नीतियाँ दल के नेता द्वारा ही निर्धारित की जाती है।

दल का अपना ने द्रीय कार्यालय (Central Office) होता है। एक स्थायी दलीय परामशदायी समिति है, जो स्थानीय दलीय समाओं के निर्वाचन हेतु आधिक अनुदान स्वीकृत करती है। अनुदारदल की स्वानीय समा या निर्वाचन क्षेत्रीय समा (Constituency Association) म क्षेत्र के सभी अनुदारदलीय सदस्य सम्मिलित होते हैं। स्थानीय समा का अपना अध्यक्ष, सचिव एव को पाष्यक्ष होता है। यदि स्थानीय समाएँ निर्वाचना सम्याधी सभी आर्थिक मार बहन करने से समय होती है तो उह अपन प्रत्याशी के चयन की पूण स्वत त्रता होती हैं। ऐसी अवस्या में दलीय के द्रीय नेतृत्व प्रत्याशी के चयन में हस्तक्षेप नही करता।

दल का सबसे महत्वपूण अग 'वाधिक बलीय सम्मेलन' है। इसम स्थानीय समाओ एव कुछ अनुदार दलीय बलवो³⁷ के द्वारा प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। वार्षिक सम्मेलन म दलीय कार्यों की समीक्षा की जाती है तथा दल की नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं। अनुदार दल के सगठनात्मक पक्ष (Organisational Wing) का ससदीय पक्ष (Parlimentary Wing) पर कठोर निय त्रण नही होता है। दलीय वार्षिक सम्मेलन द्वारा काम स समा में अनुदार दल के नेता का चयन नहीं किया जाता है अपितु ब्रिटिश ससद के अनुदार दलीय सदस्य स्वय अपने नेता का चयन करते हैं। दलीय नेता के अवसान या अप किसी कारण से उसके स्थान के रिक्त होने पर इस का जो सदस्य प्रधान मंत्री बनता है वहीं दल का नेता भी होता है। उदाहरणाय, चम्बरतेन के पश्चात चर्चिल के प्रधानम त्री बनने के साथ ही साथ वे दल के नेता भी बने थ । ऐ योनी ईंडन के द्वारा 1956 ई में राजनीति से अवकाश ग्रहण करने पर बटलर के

National Union of Conservative and Unionist Association 36

सम्पूण ब्रिटेन मे लगभग 1500 अनुदार दलीय बलब (clubs) है। इनका एक एक प्रतिनिधि क्षेत्रीय संगठन का सदस्य होता है। ये बलब जनता से सम्पक 37 रखते है।

ब्रिटिश राजनीतिक दलो का कार्यक्रम एव सगठन

अनुदार दल (The Conservative Party)

यह दल परम्परावादी है। ब्रिटिश सामाजिक व्यवस्था के आधारभूत सिद्धान्ता तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति और उत्पादन के साधनो पर व्यक्तिगत नियत्रण को उचित एव अनिवास मानता है। इस दल द्वारा इन आधारभूत सिद्धाता को अपरिवर्तित किये विना ही आवश्यकतानुसार सुधार करने का प्रयत्न किया गया है। अनुदार दल 19वी सदी के व्यक्तिवादी राजनीतिक एव आर्थिक विचारी म आस्या रखता है । वे समाजवादी व्यवस्था तथा राज्य हारा आधिक मामलो के नियम्त्रण के विरुद्ध है। यह दल राष्ट्रीयकरण का सामा यत विरोधी है परातु इसने कुछेक उद्योगा का-पया, 1927 ई मंबी की सी (British Broadcasting Corporation) एव 1926 ई में विद्युत बोड का—राष्ट्रीयकरण किया था। अनुदार दल समाज मे वग भेद की प्राकृतिक एव अनिवाय मानता है, लेकिन वग भेद को वे क्षमता पर आधारित मानते हैं। वे वग-समावय, न कि वग भेद मे विश्वास करते हैं। राष्ट्रीयता एव साम्राज्यनाद इस दल के मूल मात्र हैं। यह दल उपनिवेशों की स्वतात्रता का विरोधी था। लेकिन इघर फूछ वर्षों से उसने उपनिवशा को शीझतापूर्वक स्वत नता प्रदान की है। ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल की स्थापना एव स्थायित्व का वह पक्षपाती है, साथ ही साथ ग्रेट ब्रिटेन की युरोपीय साभा वाजार की सदस्यता का समयक है। इस दस की प्राचीन घासन व्यवस्था म पूण आस्था है अर्थात राजा, लॉड समा एव ब्रिटेन के स्यापित चच का समयक है। फाइनर के अनुसार "अनुदार दल काउन, राष्ट्रीय एकता, (ब्रिटिश) चच, शक्तिशाली शासकीय वर्ग एव राज्य-हस्तक्षेप से स्वरा न 'निजी सम्पत्ति' के सिद्धान्ती का समयन करता है।" व्यापारी एवं उद्योगपति, वैको एव घराव उद्योग से सम्बर्धित उद्योगपति, नूतीन-वंग, पादरी, साम्राज्यवादी, सैनिकवादी एव व्यवसायी अधिकाशत इस दल के सदस्य हैं। श्रमिको का भी कभी कभी इस दल को समयन प्राप्त होता है। रित्रयों के मताधिकार के पश्चात दल के समयकों की सख्या में वृद्धि हुई है। दल का युवक वग प्रगतिशील नीतियो का समयक है। 1947 ई म दल द्वारा औद्योगिक घोपणापन प्रकाशित किया गया था । दल ने इसम के द्वीय नियोजन (Planning) के सिद्धात को स्वीकारा था। 1951 इ. म अनुदार दल ना 'जुनाव घोषणा-पत्र निम्न ब्रिटेन की पून विश्व नेता के पद पर प्रतिष्ठित करना तथा आधिक पुनरद्धार करना। दल ने सोवियत रूस के साथ मिनतापण सम्बाधा की कल्पना की थी। आत रिक क्षेत्र म लोहा एव इस्पात के राष्ट्रीयकरण को निरस्त करने, कोयला राष्ट्रीय-करण को कायम रखने तथा भविष्य मे राज्य-स्वामित्व पर पूण प्रतिवन्ध का वचन दिया था। इसके अतिरिक्त लामाश पर वतमान कराधान की दरी को सशोधित तथा

I

³⁵ Finer op at, p 312

एनाधिकार को सीमित करने और प्रतिवय 3 लाख आवास मुहो के निर्माण का वचन दिया था।' उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि अनुदार दल ने भी परिवर्तित परि-स्थितिया में अपनी नीतियों में परिवर्तिन किये है पर बुदल के मूल सिद्धा तो में सहज ही कोई परिवतन नहीं हुए है। अत अनुदार दल भी सुधारवादी है पर बुदह सजगता में कदम उठाता है।

सगठन—अनुदार दल दक्षीय नेवा के चारो तरफ के द्वित होता है। एक बार जो दल का नेता नियंचित हो जाता है वह आजीवन इस पर पर बना रहता है। दक्षीय नेता को क्यापक साक्तियाँ प्राप्त होती हैं। सगठन पे अध्यक्ष को उसी के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अपनी इच्छानुसार वह अपने पद से त्यागपत्र प्रस्तुत कर सकता है तथा अपन उत्तराधिकारी को वह स्वय मनोनीत करता है। दल पी नीतियाँ दल के नेता द्वारा ही निर्पारित की जाती है।

दल वा अपना के द्रीय कार्यालय (Central Office) होता है। एक स्थायी दलीय परामदावायी समिति है, जो स्थानीय दलीय समाओ के निवधिन हेतु आधिक अनुदान स्थीकृत फरती है। अनुदारदल की स्थानीय समा या निर्यालन कीशीय समा (Constituency Association) में क्षेत्र के समी अनुदारदलीय सदस्य सम्मिलित होते हैं। स्थानीय समा अगना अध्यक्ष, सर्विच एक निर्यादक्ष होता है। दार्थ स्थानीय समा समाय होती है। स्थानीय समा समाय होती है। स्थानीय समाय सामाय समाय सामाय समाय सामाय सामा

दल का सबसे महत्वपूर्ण अग वाधिक बसीय सम्मेलन की है। इसम स्थानीय समाक्षा एव कुछ अनुदार दलीय करवी की की दारा प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। वाधिक सम्मेलन म दलीय कार्यों की समीक्षा की जाती हैं तथा दल की नीतियों निर्धारित की जाती हैं। अनुदार दल के समठतात्मक पक्ष (Organisational Wing) का समसीय पद्म (Parlimentary Wing) पर कठोर निय त्रण नहीं होता है। वलीय साधिक सममेलन द्वारा काम ससा में अनुदार दल के नेता का ज्यन नहीं किया जाता है अपितु प्रिटिश ससद के अनुदार दलीय सदस्य स्वय अपन नेता का ज्यन करते है। दलीय नेता के अवसान या अय किसी कारण से उसके स्थान के रिक्त होने पर दल का जो सदस्य प्रधान म भी बनता है नहीं दल का नेता मी होता है। उदाहरणाय, प्रचरतेन के पश्चात चिक्क प्रधानम नी वनने के साथ है सल वे दल के नेता भी यन ये। ऐ प्रोनी ईडन के द्वारा 1956 ई में राजनीति से अवकाश मुहण करने पर पर दलत के ऐ प्रोनी ईडन के द्वारा 1956 ई में राजनीति से अवकाश मुहण करने पर दलत र के

³⁶ National Union of Conservative and Unionist Association

³⁷ सम्पूण ब्रिटेन मे लगभग 1500 अनुदार दलीय क्लब (clubs) है। इनना एक एक प्रतिनिधि क्षेत्रीय सगठन का सदस्य होता है। ये बलव जनता सं सम्पक रखते हैं।

स्थान पर हैरोल्ड मैकमिलन प्रधानमात्री वने थे। बटलर दल के नेता थे परापु मैकमिलन के प्रधानमात्री बनने पर बटलर दल के नेता पद से स्वत ही हट गय थे और मैकमिलन अनुदार दल के नेता बने थे। यह एक स्वस्थ परम्परा है। इससे दल के सगठनात्मक एव ससदीय पक्षों म ग्रतिरोध उत्पन्न नहीं होते हैं।

ब्रिटिश थम दल (British Labour Party)

विटेन का श्रम दल समाजवादी दल है । यह ब्रिटिश फेवियनवाद एवं समिष्ट-वादी विचारघाराओं को सतान है। इगर्लण्ड के विभिन्न श्रमिक एवं अप समाज-वादी सभा एव सगठनो के सम्मेलन म 1899 ई म श्रमिक प्रतिनिधि सम्मेलन की स्थापना की गयी थी। यही सगठन 1906 ई म अम दल (Labour Party) कहलाया। श्रम दल समाजवाद एव लोकतात्र मे आस्या रखता है, लेकिन लोकतात्र को वे समाज वाद से अधिक प्राथमिकता देते हैं। लोकतान्त्रिक ढग से संयाजवाद की स्थापना के लिए दल कृतसङ्ख्य है। श्रम दल की नीतिया अनुदार दल के विपरीत हैं। यह दल सम्पत्ति के सामृहिक स्वामित्व एव उत्पादन के साधनो पर सामाजिक नियात्रण म विश्वास करता है और राष्ट्रीय सम्पत्ति के व्यापक सामाजिक एव आर्थिक याय पर वितरण पर बल देता है। उद्योगो एव सेवाओं के लोकत त्रीकरण का पक्षपाती है तथा हर आर्थिक दिया पर लोकता दिक निय देण स्वापित करना चाहता है। श्रम दल पूँजी वाद एवं मुनाफाखोरों का विरोधी है। इसके द्वारा एक व्यापक, व्यावहारिक तथा रचनात्मक राजनीतिक एव आर्थिक कायत्रम तैयार किया गया है। राजनीतिक क्षेत्र म वह लॉड समा का विरोधी है पर तु विगत 50 वर्षों म कई बार सत्तारूड होने पर भी थम दल इस सस्था का उत्मुलन नहीं कर सका है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह दल लॉबसमा की बक्ति को सीमित करके ही स तुष्ट हो गया है। सामाजिक सुरक्षा एव विस्तृत सामाजिक जनसवा म दल का विस्वास है। दल कमिक रूप म धीरे-धीरे विकासवादी रीति स समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का समयक है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र म शाति तथा सबक्त राष्ट्र स्थ का समयक और साम्राज्यवाद का विरोधी है। श्रमदलीय ग्रासन मही भारत स्वतात्र हुआ था। आर्थिक क्षेत्र म यडे उद्योगा के राप्ट्रीयकरण तथा एक सीमा तक भूमि क समाजीकरण का यह दल समयक है। श्रमदलीय मित्रमण्डल के कायकाल म 1946 ई म वर आफ इयलण्ड व 1948 ई म लोहा एव इस्पात तथा कायला खदाना का राष्ट्रीयकरण निया गया था। यह दल भौदाधिक क्षेत्र म लोकत व वा पक्षपाती है। श्रमिका के लिए काम के निश्चित पण्टा, पर्याप्त वतन तथा विश्राम और रुख बुद्धावस्था एव बरोजगारी के विरुद्ध बीमा याजना का समयक है। कराधान म कमदा उच्च बाय पर बधिक करारापण ना पक्ष पाती है।

श्रम दल को श्रमिका का व्यापक समयन प्राप्त है । कुछ बुद्धिवादी भी इसक

राजनीतिक दल द्विदलीय एव एकदलीय पद्धति | 1017

समयक हैं। कृपको एव मध्यवर्गीय सदस्यो की एक वडी सरया इस दल की नीतियो का समयन करती है।

सगठन-अम दल सम्बद्ध निकाया एव सगठनो का समूह है। इसकी सदस्य सस्या करीव 10 लाख है। दलीय सगठन की सबसे छोटी इकाई 'निर्वाचन क्षेत्रीय थमदल' है। इनकी सख्या 600 से ऊपर है। इन स्थानीय इकाइया के ऊपर 11 क्षेत्रीय दलीय सगठन हैं। सबसे ऊपर दल का राष्ट्रीय सगठन है। इसमे दल का के द्रीय कार्यालय है तथा दल की एक राष्ट्रीय कायकारिणी समिति है अ जिसम 28 सदस्य होते हैं । इसके 12 सदस्य श्रमिक सघी, 7 निर्वाचन क्षेत्रीय सगठनी, 1 सदस्य सहकारी सभाओं के तथा 5 स्त्री सदस्य होते है। इसके अतिरिक्त दल का नेता एव उपनेता समिति के पदेन सदस्य होते हैं। एक सदस्य कोपाध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय कायकारिणी समिति दल का नियानक एव प्रशासकीय यात्र है। इसके द्वारा के द्वीय कार्यालय का सचालन तथा दलीय कायकम का निर्धारण किया जाता है। यह दल के समस्त कार्यों का सचालन करती है। दल के 90 प्रतिशत सदस्य विभिन्न श्रमिक सघो के सदस्य होते हैं। श्रमिक सघ श्रम दल की आय के मुख्य साधन है। इस समिति के अतिरिक्त दल ना वार्षिक दलीय सम्मेलन (Party Conference) भी होता है। दलीय राष्ट्रीय कायकारिको की अनेक उप समितिया होती हैं। दलीय सम्मेलन दल की नीतिया निर्धारित करते हैं तथा दलीय सविधान को सशोधित करते है। उदार दल³⁹ (Liberal Party)

बतमान समय में उदार दल का सितारा अवसान पर है लेकिन ग्रेट ब्रिटेन के इतिहास में इस दल ने महत्वपूण भूमिका निमाई है। उदार दल अनुदार दल से प्रगतिशील एव अम दल की तुलना में अप्रपत्तिशील है। वह असवलीय नीतियां को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। मुक्त ज्यापार, नागिक स्वत नता एव पूण मताधिकार का समयक है। उदारवादियों का कथन है कि वै किसी वग का प्रतिनिधित्व नहीं करते अपितु सम्पूण राट्ड के प्रतिनिधित्व नहीं करते अपितु सम्पूण राट्ड के प्रतिनिधित्व है। वे पूणक्षेण निजी व्यापार और समाजवादी व्यवस्था म आस्था नहीं रखते हैं अपितु राट्येय आवश्यकताओं के अनुरूप दोना की विद्यालाओं के मिश्रण के पक्षपाती हैं।

स्ताठन—उदारदलीय संगठन⁴⁰ की सबंस छोटी इकाइ निर्वाचन क्षेत्रीय समाएँ हैं। दल की नीतियों में विश्वास रखने वाले किसी क्षेत्र के सभी व्यक्तिस्थानीय समाक्षा के सदस्य होते हैं। इनका अपना संगठन होता है तथा इन दलीय इकाइयों द्वारा राष्ट्रीय एवं स्थानीय निर्वाचनों में दलीय प्रत्याशियों का चयन किया जाता है। निर्वा

³⁸ The Organisation of Political Parties in Britain, C O I, R 4769, 1960, p 7

³⁹ lbid , p 6

⁴⁰ Ibid , pp 4, 5

चन क्षेत्रीय इकाइयो के उपर 12 प्रावेशिक दक्षीय समठन हैं तथा राष्ट्रीय समठन सबस शीप पर है। दक्षीय वार्षिक अधिवेशन (Assembly) दक्षीय मीतियो की निर्धार्थित करता है, दक्षीय पदाधिकारियों का निर्वाचन करता है तथा के द्रीय समिति के 30 सदस्यों का चयन किया जाता है। इस के द्रीय समिति का काय देश के प्रत्येक माग म उप्र उदारवादी विचारधारा का प्रचार एवं प्रकार करता है। इसके अतिरिक्त समकाशीन प्रको पर के द्रीय समिति जवार एक भे पक्ष को प्रस्तुत करती है तथा के द्रीय समिति द्रारा दक्ष की कायस्या का प्रचार करती है। के द्रीय समिति द्रारा दक्ष की कायकारियों समिति का यो निर्माण किया जाता है।

उदारदलीय नेता का चुनाव ससद के सदस्यो द्वारा किया जाता है 1 वह विजीय सम्मेलन की अप्यक्षता करता है तथा दल के सगठनात्मक एव ससदात्मक एको न समन्वय स्वापित करता है। निम्न आकड़ों से यह स्पष्ट है कि उदार दल ब्रिटिश राजनीतिक रजनव से तराहित होता जा रहा है, किया स समा ने उदार दल कि 1906 ई म 397, 1911 ई में 271, 1923 ई म 158, 1929 ई म 59, 1931 ई म 37, 1945ई में 12, 1964 ई में 91 और 1966 ई में 12 सदस्य में।

इगलण्ड में साम्यवादी दल भी है पर तु वह लोकप्रिय नही है। जय देशों के साम्यदादियों की फाति यह वाक्सवाद लेनिजवाद म विश्वास करता है और सवहारा वग के अधिनामकस्य एवं वग संघण का समयक है।

सयुक्त राज्य अमेरिका की वलीय व्यवस्था

अमेरिकी सिवधान निर्माता राजनीतिक दलो के विरुद्ध थ । वे दलो को लोक त के लिए अपरिहाय नहीं मानते थे । वे दलीय हिसा एव आउक से मुक्त शासन वाहुते थे । वाश्विष्ठ (Washington) एव मेडीक्स (Masison) पीनी है दला की स्थापना के विरुद्ध थ । अपन अमेरिकी रास्प्रति वाधिगटन का कथन या कि "राजनीतिक दल वैमनस्य, विज्ञाह एव तुर्जाव के मुल हाते है।" इनसे वचकर रहुना चाहिए। अस वंजनस्य, विज्ञाह एव तुर्जाव के मुल हाते है।" इनसे वचकर रहुना चाहिए। अस वंजनस्य, विज्ञाह एव तुर्जाव के मुल हाते है।" इनसे वचकर रहुना चाहिए। अस वंजनिक जनकी यह आकाशा कवक मग मारीविका ही सिद्ध हुई । 1796 ई में रास्त्रपति के निर्वाचन में यो राजनीतिक दलों के प्रत्याधिमों के इस में जान आदम रिवाच में ति अपने का लेक स्वाचित्र ही सिद्ध हुई । 1796 ई में रास्त्रपति हो सर्वोचिक राजन पर दल अवविद्ध हो को यो राजिया के आठवें वय में ही अमरिकी राजनीतिक राजन पर दल अवविद्ध हो कुक में । दलीय व्यवस्था को भूमिका दससे यूव फिलाडेबिक्स सम्मेलन में ही पड चुकी भी । सम्मेलन में प्रतिनिधया का एव समूह यदि राज्यों को अधिकाधिक स्वाचत्ता होने को समयक पा तो दूसरा समुह हाफिखालों के दीव वास्त के निर्माण ना पत्थाची या। प्रथम समुह सम्वविध्यों (Anti Federalist) एव दितीय समूह सम्वचिध (Federalist) के नाम से विस्थात थे। अफरसन 'या विरोधी' यह हीनस्टन 'यम वारी' समुही के नेता थे। 'यध विरोधी' यू इसलव्ह एव मह्यवर्धी राज्या के औरो

गिक, व्यापारिक एव आधिक हितो के सरक्षक थे, तो 'सघवादी' कृपको, वगीचो के स्वामियो एव उत्तरी ग्रामीण और दक्षिणी कृपक हितो के पक्षघर थे। स्मरणीय है कि राष्ट्रपति जॉज वाशिगटन अपने द्वितीय राष्ट्रपति काल मे राजनीतिक दलो के प्रमाव को स्वय अनुमव करने लगे थे। सघवादी जान आदम 1796 ई म राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे और आगामी निर्वाचनो (1800 ई) मे सघ विरोधी थॉमस जैफरसन राष्ट्रपति बने थे। यॉमस जैफरसन ने अपने दल का नाम लोकत व गण-त तीय दल (Democratic Republican Party) रखा । यही दल बाद में लोक त त्रीय या डेमोकेटिक दल (Democratic Party) कहलाया। सघवादी दल 1812 ई के निर्वाचनों में उमरा या और यही दल जकसन के राष्ट्रपति काल मे द्विग दल (Whig Party) तथा 1854 ई म रिपब्लिक्त दल (Republican Party) कहलाया । सचवादियो का प्रमाव धीरे धीरे कम होता गया और 1816 इ मे वे समाप्त हो गये। सन 1816 30 ई तक देश म कोइ स्पष्ट राष्ट्रीय दल नही था, केवल छोटे छोटे दल समूह थे जिनका नेतरव आदम, क्ले, जकसन एव कोल्हुन जैसे राजनीतिज्ञ कर रहे थे। वतमान काल मे राजनीतिक दल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था के अनिवाय अंग है। इहोने सविधान को गतिशीलता एव शासन के विभिन्न अगो म सामजस्य स्थापित किया है तथा उसे एकरूपता प्रदान की है। विशेपताएँ

अमेरिकी दलीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ निम्नवत हैं

(1) सयक्त राज्य मे प्रारम्म से ही दिस्लीय पद्धति और मुख्य राजनीतिक दल-डेमोर्नेट एव रिपब्लिकन-हैं। लेकिन अनेक छोटे छोट दला का भी सदैव अस्तित्व बना रहा है । उदाहरणाथ, मदा निर्पेध दल (Prohibition Party) का उदय 1872 ई म और अत 1933 ई में हुआ था। आज भी अमेरिका में साम्यवादी दल, समाजवादी श्रमिक दल, समाजवादी लोकतात्रिक दल तथा अय विभिन्न श्रमिक समूह हैं। द्विदलीय पद्धति के विकास के कई कारण हैं (1) द्विदलीय पद्धति औपनिवेशिक काल की दन है, (11) आग्न मापाभाषी देशों की जनता म समभौतावादी मनावृत्ति अधिक होती है और वे कम कल्पनाशील होत है, (111) अमरिकी राप्ट्रीय जीवन म धम, राप्टीयता. वश आदि की मावनाए उतनी उम्र नहीं हैं जितनी युरोप म हैं, (1v) अमेरिकी विधानमण्डला की निर्वाचन-पद्धति ने भी द्विदलीय पद्धति क विकास म योग दिया है। विधानमण्डल के सदस्य एकल सदस्यी जिला निर्वाचन याजना क अनुसार निर्वाचित किये जाते हैं, फलस्वरूप छोट छोटे दल निर्वाचन म माग लेन नी स्पिति म नहीं हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन निवाचक मण्डल द्वारा होता है। यदि देश म तीसर दल का उदम हो जाता है तो राष्ट्रपति का निवाचन विकन हो जायेगा । विसी प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होन की बबस्या म प्रतिनिधि सदन का राष्ट्रपति को निर्वाचित करने का अधिकार होता है। बहुदलीय पद्धति क जातात या दिदलीय

पद्धति के अभाव में राष्ट्रपति के निर्वाचन म सोदेवाजी की प्रधानता हो जाने वो आशका है। (v) सत्ता के लिए तीज़ प्रतिस्पर्धा के कारण महत्वाकाक्षी राजनीतिक समुद्दा, वर्गा एवं हितों का सहज ही घूनीकरण (centralisation) हो गया है।

- (2) अमेरिकी राजनीतिक दला म सुस्पष्ट जातर नहीं है और न वे स्पट आधारभूत सिद्धा तो पर ही जाघारित हैं। दोनो ही दल लोगता त्रिक हैं परन्त उनकी विचारधाराओं में कोई निविचत एवं स्पष्ट भेद नहीं है। अमेरिकी दल सिद्धाता की अपेक्षा हिता की समानता एव एकता पर आधारित है। भी बीयड का कथन है कि दोनो दलो की नीतियो एव कायत्रम की अपेक्षा एक ही दल के विभिन्न पक्षी के हप्टि-कोणा म कही अधिक मतभेद है। वां स्वाइस ने इसी विचार को व्यक्त करत हुए कहा है कि दोनो अमेरिकी दल "दो खाली बोतला के समान हैं जिनम प्रत्यक पर दो मित प्रकार की दाराव क लेबिल चिपके हुए हैं।"" फाइनर के अनुसार "अमेरिका में तो वास्तव म केवल एक ही दल रिपब्लिकन इमोक्षटिक दल (Republican cum Democratic Party) है । वह अपनी बादतो एव सत्ता की प्रतिस्पर्ध के कारण दो समान भागा मे विभाजित हैं, एक का नाम रिपब्लिकन और दूसर का नाम डेमोफेटिक दल है।"48 इस मत का समयन दोना दला के अग्राकित कायच्या एवं उनके श्रमिक विवास के विवरण से भी स्पष्ट होता है। लेकिन यह मत पूणत स्वीकाय नहीं है। दोनो दला में तात्रालिक एव विशिष्ट हितों की हृष्टि से अल्पनालिक अतर तो हाते हैं परन्तु दोनो दल लोकत त्रवादी, गणत त्रवादी, मौलिक स्वतात्रतात्रा के समयक वयक्तिक पूजी के आधारभूत अधिकार की धारणा में विश्वास रखने वाले, उदारवादी, सविधानवादी, सपुक्त राष्ट्र सघ और विदव शांति के समयक हैं। दोना ही दल पूजी वादी अथ व्यवस्था को स्वीकारत हैं। प्रो बीयड का यह कथन कि दोनो दला मे नामा के अतिरिक्त अय कोई अ तर नहीं है सत्य नहीं है। इसका केवल यह तारपय है कि समय समय पर उनकी नीतियों में अन्तर होते रहे हैं। परत् यह भेद वे अन्तर लोकन तीय गणत त्रीय विचारधारा के व्यापक वातायन के अ तगत ही हैं।
- (3) अमिरिका में दलो का आधार समूहबात हित अर्थात आधिक हित है। धार्मिक, राजनीतिक तथा स्वमानवात मेदमाब पर क्लीय व्यवस्था आधारित नहीं, है। सामा यत रस ?ो हितो पर आधारित हैं—शोधोगिक एव कृषि । दक्षिणी रियासते अधिकायत कृषि प्रधान हैं अत यहीं पर हेपीकेटिक दस अधिक सहित्य है। वक्तरी पूर्वी अमेरिका औद्योगिक क्षेत्र है अत इस क्षेत्र के उत्पादका, साहुकारा एव अधिक हिती ना सर-

⁴¹ Prof C A Beard American Government and Politics p 67

⁴² They are like two bottles, each with different lables and both are empty Lord Bryce, cited by H Finer p 353

⁴³ H Finer, cited by V D Mahajan op cit, 1966, p 267

क्षण आवश्यक है। फलत इस क्षेत्र एवं समस्त उत्तरी क्षेत्र मं रिपह्लिकन दल अधिक लोकप्रिय है। बीघड का यह मत है कि शासन का सद्धातिक स्वरूप अमेरिकी दलों का तानाशाना नहीं हैं अपितु दला के नेताला का व्यक्तित्व एवं दलीय समस्याएं दला का तानाशाना है। ⁶⁴ दोनो दल सभी क्षेत्रों व प्रदेशों के नागरिका के मतो को प्राप्त करने का प्रयन्त करते हैं। फाइनर के अनुसार "संयुक्त राज्य अमेरिका में दलीय उदेग कस है, मतदाता पच्चमजुजुआ वर्षीय है वे उत्र दाक्षनिक सिद्धान्तों एवं विचारों से प्रमावित नहीं होते हैं।"

(4) अमेरिकी राजनीतिक जीवन म ज्याप्त लूट प्रणाली (Spoils System) का राजनीतिक वलो से चिनस्ठ सम्ब ध या । 19वी सदी मे इस प्रणाली के फलस्वरूप राजनीतिक जीवन अत्यधिक भ्रन्ट हो गया था । वतमान काल मे तो इस प्रणाली की बुराई बहुत कम है । लूट प्रणाली के अ तगत नव निवंचित राष्ट्रपति अपने पूबगामी हारा नियुक्त सासकीय अधिकारियों को हटांकर उनके स्थान पत्नीन कामपीयों को नियुक्त करता था और इस प्रकार अपने समयका, सहयोगियों, निवंचिनों मे समयन एव प्रचार करते वाला को शासकीय पदी पर नियुक्त करके पुरुक्त करता था । नियुक्तियां का आधार योग्यता न होकर दलव दी हुआ करता था ।

अमेरिकी दलो के कायकम तथा नीतियाँ

अमेरिका भ दो ही प्रमुख दल हैं। देश की राजनीति में समय-समय पर दोनों में से किसी न किसी दल का प्रावत्य रहा है। प्रारम्भ में हैमिस्टन सपवादिया एवं जैकरसन सम विरोधी दल (अमोकट रिपिल्लकन) के नेता थे। 1800 से 1824 ई तक रिपिल्लकन दल पवास्था रहा । 1828 से 1840 ई तक डेमोनेट दल का देश की राजनीति में प्राधा य रहा था। 1850 एवं 1860 के दशका में वासता का प्रमुख को राजनीति को प्रमुख समस्या थी। रिपिल्लकन दल दासता के उम्मुलन का समयक था। लेकिन डेमोनेट दासता को कायम रखन के पक्षपाती थे। यदि डेमोनेट दल ने कुछ उदार इंटिकोण अपनाया होता तो खायव वह सता म बना रहता। रिपिल्लकन दल के थी लिकन के राट्यति चुने जाने पर उत्तान दासता को समयच घोपित किया। इसते दल को अत्यिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। एन बार सता म आने पर दल न अपनी स्थिति को सुटट किया और 1885 ई तक परास्व रहा। 1889 से 1893, 1899 से 1912 एवं 1922 से 1932 ई के रिपिल्लकन दल सत्ता म रहा। 1952 से 1960 एवं 1968 से 1974 ई क कायकाल म यही दल पुन सत्ता इसा इंटे हे वा वासता न अमेरिका के राट्यपित पर पर रिपिल्लकन दल सत्ता म रहा। 1952 से 1960 एवं 1968 से 1974 ई क कायकाल म यही दल पुन सत्ता इसा इसा दल हो। वतमान म अमेरिका के राट्यपित पर पर रिपिल्लकन दल के राट्य पित पर पर पर स्वार्ट दल से राट्य पित पर पर स्वार्ट दल से राट्य पित पर पर स्वर्ट हो। वतमान म अमेरिका के राट्यपित पर पर रिपिल्लकन दल के राट्य पित पर पर स्वर्ट है। उपरोक्त अवधिया के मध्य के काल म डेमानेट दल सत्ता म

⁴⁴ Beard cited by V D Mahajan op est, p 265

⁴⁵ Finer op cit, p 357

रहा है। दोता बता मा। "ा कं प्रमुन साटुशति हुए हैं, यथा—अफरसन, सिकन, आइजाहारर एव निससन रिपब्सिका बस कं और विस्सन, फॅंगिला ही रूजवस्ट, ट्रूमा एवं नैनही हेमोनेट बस के प्रस्तात सप्ट्रपति थे।

श्रेमोफटिक वस (Democratic Party)

अप! प्रारम्भिन काल म यह दल समीय शासन की शक्ति म वृद्धि, साम्राज्य यात, रशित स्थापार एय बहुावा ने लिए भाषित अनुवान दन की नीति का विरोधी था। दातता न प्रत्न पर इस दल न उसके उन्नुलन का विरोध विधा था। फलस्वक्य कई दासन सम्भित्ती राजनीति म हसका प्रमाव संत्यिक कम हो गया था। इस दल न उनीसवर्ग नदी राजनीति म हसका प्रमाव संत्यिक कम हो गया था। इस दल न उनीसवर्ग नदी म उपका के हिता को सरस्व प्रदान किया था। प्रयम विदव युद्ध वाल म राष्ट्रपति विस्तान ने परम्परायत विदेश-गीति म परिवतन किया था। वह म तर्राष्ट्रीयता एव विदय शानित का समक्ष था। वेमोत्रेट राष्ट्रपति एक बी स्वजनेत्व न विदयस्थापी आधिक म यी से राष्ट्र के उद्धार हुत 'नदीन कार्यक्रम' (New Deal Programme) के अभीन कार्यिक मामला म राज्य के हस्तक्षेप का समवन किया था। रिपिन्तकन दल की अपका डेमोत्रेट दल न संधीय शासन समयक नीतिया का अधिन निर्माण किया है। 1952 ई म बेमोत्रेट दल न शितशासी नुरक्षा योजना द्वारा पूरापीय देशों की सावियत साम्राज्यवाद से गुरक्षाय सामृद्धिक नीति का अनुगामन किया था। विद्य शानित को दल ने अपना प्रमुख सदय पीयित किया था। आज भी दल इन नीतिया का समर्थक है।

रिपब्लिकन दल (Republican Party)

प्रारम्भ में यह बत धनिवधाली संपीय सरकार का समयक था एवं सिवधाल की उदार व्याक्या पर बन देता था। सिकन के राष्ट्रपति बनन पर इस दल का वास्त- विक उद्भव एवं विकास हुआ और 1860 हैं से 1913 हैं तक थीड़े से अतराल (केवल आठ वर) से यह दस स्तान आधिक अनुवान देन, दासता-उ मुलन, नीघों को मताधिकार देन की नीति का समयक है। इसी दल के कायकाल में दासता का उ मुलन हुआ था और 1860 से 1865 हैं तक अमेरिकी युहु-युद्ध लडा गया था। इस गह युद्ध में उत्तरी राज्यों की सफलता ने अमेरिकी राष्ट्र को विधित होने स जमा लिया। 19वी सदी के अपने कायकाल में इस दल के समक्ष दो बढी कठिनाइयों आयों थी (1) राष्ट्रपति आपट के शासन काल में ज्याप्त फ्रप्टाचार, एवं (2) आतरिक दलीय विभेद । दल म अनेक समूह थे जो परस्पर विरोधों के अत उनम तीय मतिक है। विभन्न खताब्दी के अतिम काल में ब्रिक्ट को के दिन साल में ब्रिक्ट होने से वचा था। 1952 हैं में रिपब्लिकन दल ने डेमोक्टिक साल में ब्रिक्ट होने से वचा था। 1952 हैं में रिपब्लिकन दल ने डेमोक्टिक साल में ब्रिक्ट होने से वचा था। 1952 हैं में रिपब्लिकन दल ने डेमोक्टिक साल में ब्रिक्ट होने से वचा था। विभिन्न के तथरा एशिया सम्बंधी अमेनिटक दल की विदेश नीति को अवस्थक उद्यावा था। राष्ट्रपति तिनवत ने अपने अमेनिटक दल की विदेश नीति को अवस्थक उद्यावा था। राष्ट्रपति तिनवत ने अपने

कायकाल म साम्यवादी चीन स मत्री नी तथा रूस एव चीन से सम्ब घो म सुधार, तथा विगतनाम समस्या ने समाधान के सफल प्रयत्न किये थे।

योना दला भी विदेश नीतिया एव कायभमा म बहुत अतर नही है। उनकी विदर्स नीतियाँ तात्नालिक प्रस्तो से अधिक सम्बिध्त होती हैं। राष्ट्रपति वित्सन ने अतराष्ट्रीयता एव राष्ट्र सघ की सदस्तता का समधन किया था, लेकिन रिपिल्कन दल का बहुमत रखने वाली सीनट न उनके हारा सम्यादिव वासांयी सिंध को अस्वीकार करक राष्ट्र सघ को सदस्तता का अस्वीकृत कर दिया था। आतरिक नीतियो के सम्बाप म दला म अपशक्त अधिक मत्रमेद होते हैं। राष्ट्रपति क्रिकिन नीतियो के सम्बाप म दला म अपशक्त अधिक मत्रमेद होते हैं। राष्ट्रपति क्रिकिन नीतियो के सम्बाप म दला म अपशक्त अधिक सत्योग द्वारम सामाजिक करवाण के हेतु ब्यापक भूमिका वा प्रतिपादन किया था। रिपिल्वकन दल का इसके विपरीत यह तक था कि इससे निजी व्यापार को हानि होगी। दोना दलो की आन्तरिक नीतियो एव कायकमा म अपशक्ति क तर रहत हुए साम्य भी है। दोनो दल सामाजिक सुरक्षा के सम्बाप म दोनो दला म क्य-वह मत्रभेद हैं। रोना अमेरिकी दल को केतन म, वैयक्तिक पूजी एव पूजीवादी व्यवस्या के समथक है तथा समाजवाद पत्र मान्यवाद प विरोध है।

दक्षीय सगठन—धोना दला का सगठन पिरामिडाकारहै। दलीय सगठन के चार प्रमुख स्तर ह । सबसे निम्न सल पर प्रेसिक्ट समितियाँ (Precinct Committee) ह । प्रेसिक्ट मतदान पा सबसे छोटा जिला है । इस सिमित के प्रमुख को प्रेसिक्टमेन (Precinctman) कहा जाता है । प्रेसिक्ट समितियों के उत्पर जिला, काउन्दी तथा राज्य की के प्रीय सिमितयों होती है । सबसे छोप पर दल की राष्ट्रीय सिमित है । इसके अितरिक्त दल का अध्यक्ष एव कायकारिणी सिमित होती है । प्रतिनिध सदन एव सीनेट हे निर्वाचना म प्रचार सम्बर्ध पत दलीय सिनियों की होती हैं । योगो दलों के राष्ट्रीय सम्मेशन (National Convention) होत ह । वे ही दलीय नीति निर्धारित करता है । दला की राष्ट्रीय समितयां हो राद्री मिया जाता है ।

राष्ट्रीय समिति दल का स्थायी सगठन होता है। इसमें प्रत्येक राज्य एक पुत्रप एव एक स्त्री को प्रतिनिधि के रूप भ जेजत है। राष्ट्रीय समिति के अप्यक्ष काम राष्ट्रपति पद के दलीय जम्मीदवार द्वारा चुना जाता है और दल की समिति करिती को अध्यक्ष पद पर जुन जेती है। दलीय अप्यक्ष निर्वाचनों में दल की च्यूह रचना के लिए उत्तरदायी होता है। राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष दल का प्रमुख रोता नहीं होता अपितु वह कंपल दलीय सगठन का प्रतीक है। राष्ट्रीय समिति का सिद्धात में व्यापक इतिकर्ष प्राप्त है पराजु व्यवहार में इसका काय केवल राष्ट्रपति पद के लिए नामजदारी का अनुमोदन तथा दलीय राष्ट्रीय सम्मेतन को आयोजित करना मान है। निर्वाचन सम्बन्धि मामका में राष्ट्रीय समिति का क्षेत्र राष्ट्रपति के निर्वाचन तक ही सीमित है।

अमेरिकी यसा म सामा यस सत्ता एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह म केद्रित होती है और दसीय यात्र के माध्यम से इसका नियानण किया जाता है। ऐसे राजनीतिक दसीय अपिनामक को वास (Boss) एव समूह को काक्स (Caucus) या रिंग (Rung) कहते हैं। ये दलीय वाँस अंद्र्यापर, रिश्वत, कठोर दलीय निर्वाचन एव सरक्षण (patronage) प्रदान करके अपनी सत्ता को बनावे रखते है। प्राय इनके द्वारा विमिन्न निर्वाचन से इलीय उम्मीदवारों का चयन किया जाता था। विगत सतादित्या म निर्वाचन के इन दोषा को दूर करन के लिए कई सुधार किये यये हैं, उदाहरणाय— दसीय नेता द्वारा दसीय उम्मीदवारों के चयन के स्वान पर प्राइमरी निर्वाचन (pri mary elections) का सूत्रपात किया गया है। प्राइमरी निर्वाचनों म विमिन्न निर्वाचनों के सम्बाध म वलीय उम्मीदवारों के विषय म दलीय सदस्यों द्वारा निर्णय निर्णे जाते हैं। राज्या द्वारा प्राइमरी निर्वाचनों के सम्बाध में विभिन्न किया गया है। इस प्रकार के निर्वाचन प्राय सामाय निर्वाचन के दो या तीन माह पूत्र होते हैं। प्राइमरी निर्वाचनों में जिस दलीय व्यक्ति को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं वहीं उसमीदवारों होते हैं। अप्रहमरी निर्वाचन में जिस दलीय व्यक्ति को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं वहीं उसमीदवारों होते हैं। स्राप्त निर्वाचन से लिया वसी को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं वहीं उसमीदवार होता है।

अमेरिकी राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश दला की मीति सुतगठित एव अनुसासित नहीं हैं। फलस्वरूप दलीय सदस्या के मध्य महत्वपूण प्रश्ना पर मत भेद होते हैं। परंतु काउण्टी एव नगर-स्तर पर दला केसगठन अपेक्षाकृत सुसगठित हैं। एकदलीय पद्धति

(ONE PARTY SYSTEM)

एकदलीय पढ़ित में देश में एक ही दल होता है एवं उस राजकीय सरक्षण मी प्राप्त हाता है। इस प्रकार की व्यवस्था साम्यवादी देवों एव दिसीय विश्व युद्ध के पूव जमनी एवं इटली तथा द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरात्त एवियाय एवं अफ़ीका कुछ नवीदित स्वतंत्र राष्ट्रा य पायी जाती है। माजी जममी तथा फासिस्ट इटली में एकदलीय व्यवस्था थी। सोवियत क्ष्य, साम्यवादी वीन तथा पूर्वी पूरोप के अनेक देशों में केवल साम्यवादी वल का ही अस्तित्व है। एकदलीय व्यवस्था सवप्रयम सोवियत स्व में स्थापित हुई थी। इसके पश्चात फासिस्ट इटली (1923 43) एवं नाजी जमनी (1933 45) में एकदलीय व्यवस्था स्वाप्त हुई थी। इसके पश्चात फासिस्ट इटली (1923 45) एवं नाजी जमनी (1933 45) में एकदलीय व्यवस्था रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भागा⁴⁶, वीनिया⁴⁷, वर्मी आदि देशा म एकदलीय व्यवस्था रही है। वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भागा⁴⁶, वीनिया⁴⁷, वर्मी आदि देशा म एकदलीय पद्धति को स्वीकार

⁴⁶ राष्ट्रपति नक्रमा के समय मे पाना मे एकदलीय ब्यवस्था स्थापित की गयी थी।
युगाण्डा मे दतीय अधिनायकत्व तो नहीं किन्तु व्यक्तिगत अधिनायकत्व है।
47 कीनिया में भी एकदलीय व्यवस्था है।

एक्दलीय पद्धति की प्रमुख विशेषवाएँ निम्नवत है 48

(1) दला की स्थापना के पूत्र ही सामा यत उनके उद्देश्यों की शोषणा कर दी जाती है परन्तु एकदलीय पढ़ित म दता की स्थापना के पश्चात ही उसके मिद्धा तो का निरूपण किया जाता है। उदाहरणाय, मुसोलिनी में सत्तास्व होने पर ही फासीबाद के सिद्धा तो नो निकसित किया गया। 10 सोवियत स्था म भी 1917 की जाति के पश्चात साम्यवादी दल ना एकाधिकार है तथा 1936 ई के सविधान द्वारा साम्यवादी दल को विधिक मान्यता प्रदान की गयी है।

(2) एकदलीय व्यवस्था में दल एवं शासन में सीधा एवं स्थायी सम्बंध होता है। दोनो एक दूसरे से सम्बन्धित होते हैं और शासन पर दल का पूण नियात्रण होता है।

(3) दलीय अनुशासन कठोर होता है तया दलीय नेताओं की उपासना की जाती है।

(4) सत्ता का प्रवाह अपर से नीचे की ओर होता है।

(5) विरोधी दलो, विचार-स्वात य एव विचारों की अभिव्यक्ति तथा अय व्यक्तिगत स्वत अताओं का निममतापुवक दमन किया जाता है।

एकदलीय पद्धति का उदय एव विकास

यूरोपीय महाद्वीप में ग्रेट ग्रिटेन तथा का स को छोड़कर किसी भी देश में सासत का सफल सवालन सम्मव नहीं हो सका है। दिवलीय एव बहुदलीय पढ़ित की असफलता इसका प्रधान कारण हैं। इलीय शावन की सफलता के लिए यह निवात आवर्षण है कि मतदालाओं में सामाजिक लक्ष्यों और राजनीतिक आदर्शों के विषय में मतैवय हो। यदि मतदालाओं में सामाजिक लक्ष्यों और राजनीतिक आदर्शों के विषय हो। यदि मतदालाओं में दामाजिक लक्ष्यों और राजनीतिक आदर्शों के विषय हो। यदि मतदालाओं में दामाजिक लक्ष्यों की राजनीतिक आदर्शों के सिक्त सामाय लक्ष्यों की स्वीकार करते के लिए तैयार व हो तो दलीय शासन की सफलता सदिव्य है। दितीय विषयमुद्धके उपरात यूरोपीय देशों की जनता में इन राष्ट्रीय लक्ष्यों के सम्बाध मंत्रीत मतत्रेद उल्लान हो गये थे। विभिन्न विचारों एवं सिद्धी तो तथा नेतृत्व के लिए होने वाली सध्यों में दला द्वारा एकता एवं व्यवस्था की स्वापना की जाती है तथा दे शासन के निर्माण को सम्मव बनाते है। वनता को अपने विचारों के अनुकूल बनाने में सफल होना वाला दल निर्वाचों में बहुनत प्राप्त करते में सफल होता है तथा सत्ता हस्त्याव करता है। प्रथम विवस्य दे के उपरात पूरोपीय देशा में वाहित राष्ट्रीय एकता, सास्कृतिक सहयोग तथा लातीय एवं धारिक सहिष्णुता का अभाव

⁴⁸ Maurice Duverger Political Parties Book II

⁴⁹ नाजीवाद के सिद्धातों के बारे मं यह मत सत्य नहीं है। हिटलर ने अपनी आत्मकथा (Mein Kempt) मं अपने विचारा एवं सिद्धातों का सत्तारूढ़ होन के पूत्र ही उत्लेख कर दिया था।

या, फलस्वस्प विभिन्न दल परस्पर सहमत न हो सके तथा प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात इटली एव जमनी म एक के वाद एक लोगतन्त्रीय शासन क्रमश धराशायी होते गये। 1917 ई में लाल क्रांति के पश्चात रूस ये साम्पवादी दल की सत्ता स्थापित हुई थी।

इटली मे एन दलीय व्यवस्था ने उदय के निम्न कारण थे

(1) पोप ने इटसी की सरकार द्वारा पोप के प्रदेशा को छीनने के कारण कैंथोलिक मतदाताओं का मत देने से वॉजत कर दिया था तथा मुसोलिनी की सरकार को मा यता प्रदान नहीं वी थी।

(2) इटली के विभिन्न दल राष्ट्रीय सगठन न रहकर जी हुज्रों के समूह वन गये थे। जनता म सामाती मनोवृत्ति का प्राधान्य था। प्रतिनिधि समा के सदस्य मित्रयों से अनुचित लाम प्राप्त करने के लिए ससद म उनका समयन करते थे। इटली का ससदीय जीवन श्रष्ट हो चुका था।

(3) अपने की सत्ता म रखने के लिए म नीवण सबद मे एक गुट को दूसरे से लडाते रहते थे । फलस्वरूप दला के कायकम राष्ट्रीय इप्टि से निर्धारित म किये जाकर दल के प्रमुख नेताओ द्वारा अपने व्यक्तिगत हितो की इप्टि से निविचत किये जाते थे । मामा य जनता मे ससदीय जीवन एवं "यवस्या के प्रति तीव अस तोप था ।

1919 ई म इटनी में समाजवादी सबसे वही सत्या में ये और समाजवादी दल सबसे बडा दल या। परत् उनमे मतनय नहीं था। वेएक दूसरे की आलोचना करते रहते थे। कोई दल सवसम्मत कायकम स्वीकार करन को तैयार नहीं था। मुसी लिनी ने फासी रून की स्थापना की थी। 1920 ई म इटली म साम्यवादियों के नेतृत्व म अनेक हडताले आयोजित की गयी । देश में कान्ति की हवा तीव गति से चल रही थी। इसी समय हडतालिया एव कारखानेदारों में समभौते हो गये। शासन की असफलता स्पष्ट हो गयी थी। इन अराजक परिस्थितियों में मुसोलिनी को अपने दल को सशक्त बनाने का अवसर मिल गया । अपने विरोधियो---समाजवादियो एव साम्य-वादियो-के विरुद्ध मुसोलिनी ने सीधी कायवाही के अस्य को अपनाया। उसका नारा था 'लाल खतरे से सावधान' । उसने हडतालो को दबा दिया तथा सम्पत्ति के अधि-कार को स्वीकार करने नी माग की । इनसे आर्कापत होकर उसके दल मे अनेक सदस्य शामिल हा गय । 1921 ई के पश्चात फासी दल की प्रगति दूत गति से होने लगी। राष्ट्रीय सम्मान तथा प्रतिष्ठा की रक्षा का उसने शखनाद किया और इटली को विश्व का नेता बनाने का वाश्वासन दिया । उद्योगपतियो ने फासी दल का समयन किया । जनेक धमिक संबठनो का भी फासी दल ने संगठन किया । 28 अक्टूबर, 1922 ई को फासिस्ट मलेशिया को सगठित करके मुसोलिनी ने रोम को घेर लिया। उसने रलवे स्टेशन, डाकखाने एव नगर पर अधिकार कर लिया। राजा ने प्रधानमंत्री के परामदा को स्वीकार करते हुए सनिक कानून की घोषणा न करके मित्रमण्डल को विघटित कर दिया तथा मुसोलिनी को नवीन मिनमण्डल बनाने ने लिए

आमिन्त्रित किया । 29 अक्टूबर, 1922 ई को मुसोलिनी मिश्रित शासन का प्रधान वना। सत्ताम आने पर उसने शीघ्र ही अपना अधिनायकत्व स्थापित कर लिया। 1924 ई म एकरवो निर्वाचन विधि (Acerbo Electoral Law) वनाने मे मुसी-लिनी सफल रहा । फलस्वरूप निर्वाचना म बहुमत प्राप्त करने वाले दल को विधान मण्डल में दो तिहाई स्थान प्रदान किये गये। इस प्रकार किसी समूह की सहायता के विना ही वहमत दल को शासन मस्पप्ट बहुमत का अधिकार प्राप्त हो गया। इसके पश्चात मुसोलिनी ने अपने एक के बाद दूसरे विरोधियों का सफाया करना प्रारम्म कर दिया। इटली में आतक का राज्य स्थापित कर दिया गया। प्रेस पर नियातण था। सभी गर-फासीवादी दलो को विघटित कर दिया गया । स्थानीय शासन को भी समाप्त कर दिया गया। सभी सरकारी कमचारियो एव विद्यालयो के प्राचायों को फासीवादी दल के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए बाध्य किया गया । 1928 ई के पश्चात चेम्बर ऑफ डेप्टीज के सदस्य फासीवादी दल की प्राण्ड समिति (Grand Committee) द्वारा नियक्त किय जाने लगे। 1939 ई मे चेम्बर ऑफ डेपुटीज के स्थान पर फासिया एवं कॉरपीरेशन सदन की स्थापना की गयी। सक्षेप मे, मुसीलिनी इटली का सर्वेसवी वन बैठा और उसने फासी दल के सहयोग से इटली म सर्वाधिकारवादी राज्य की स्थापना की । राज्य का आर्थिक जीवन पर पुण निय प्रण स्थापित किया गया तथा निगम राज्य (Corporate State) की स्थापना की गयी।

जमनी म 1919 मे अनेक दल समूह थे। वे एक दूसरे की तीव आलोचना करते थे । वीमर सविधान (Weimer Constitution) के अत्तवत राष्ट्रपति एव ससद--रीस्टाग-को चुनने का अधिकार जनता को प्रदान किया गया था। अठ सविधान द्वारा राष्ट्र के प्रत्येक समह की प्रतिनिधित्व देने का आश्वासन दिया गया था। सत्ताकाकेट कायपालिकाकी अपेक्षाविधानमण्डलको बनाया गया था। चा सलर (प्रधानम त्री) अपने मन्त्रिया सहित रीस्टाग के प्रति उत्तरदायी होता था। लेकिन रीस्टाग मे 12 से भी अधिक राजनीतिक समृह ये और सावजनिक उद्देश्या की दृष्टि से उनमे कोई समानता नहीं थी। विभिन्न समूहों क परस्पर विरोधी आर्थिक हित थे। इतम सौदेवाजी के पश्चात ही किसी प्रकार की एकता स्थापित हो पाती थी और तत्पश्चात ही कोई राजनीतिक कदम उठाना सम्भव था। मिश्रित मित्रमण्डला का निर्माण बहुदलीय पद्धति की सहज विरोपता होती है। इन मिश्रित मित्रमण्डला का कायकाल उनका निर्माण करने वाले विभिन्न समूहा के आर्थिक हितो म एकता पर निमर होता है। अत व्यवहार म मिश्रित मित्रमण्डल बल्पकालिक होते थे। जमनी में मिश्रित मित्रमण्डला के उत्थान एवं पतन होते रहत थे। 1919 से 1936 ई के मध्य तक करीव 30 मित्रमण्डल बने और विगडे थे। कायपालिका की अस्यिरता एव विधानमण्डल की अक्षमता के कारण शासन की सत्ता व्यवहार म नौकरशाही के हाथो म अनजान ही हस्ता तरित हो गयी थी। साम्यवादिया एव समाजवादिया सहित

जनता के एक वर्ग में इस स्थिति के प्रति अव्यक्षिक अस तोष जरमन हो गया था। इस बीच में 1930 ई की विष्वच्यापी आर्थिक म दी ने जमन अथ ध्यवस्था को पूरी तरह नण्ट अण्ट कर दिया था। मूल्य वृद्धि, वेरोजगारी तथा आर्थिक सकट में वस्तुओं के अमाब के कारण जनता में तीक्ष अस तीष व्याप्त था। देश में उचित एवं सशक्त नेतृत्व की कार्य था। देश में उचित एवं सशक्त नेतृत्व की कार्य था। देश में उचित एवं सशक्त नेतृत्व की कार्य था। देश में उचित एवं सशक्त नेतृत्व की कार्य था। देश में उचित एवं सशक्त नेतृत्व की कार्य था। देश में उचित एवं सशक्त विश्व की कार्य मुक्त ने लगी। सितम्बर 1930 ई के निर्वाचनों में दोस्टाल के 647 स्थानों में दे 288 स्थानों पर नाजी दल का कब्बा हो गया था। सत्तास्व होने पर इस दल ने साम्यवादियों तथा अप समाजवादी लोकता कि प्रति प्रति विश्व होने पर इस दल ने साम्यवादियों तथा अप समाजवादी लोकता किया। देश से यहूदियों, का विष्ट का लीर तालों की सख्या में उनकी हत्या भी की गयी। फलस्वक्य मृत्री जमनी की छोडकर माणने लगे थे। नाजी दल ने रक्त की शुद्धता का नारा समाया। नाजी की ने आय जाति की नोमेंहिक (Nomadic) शाखा की लमन जाति को रक्त की इदिद स अव्यत्न जाति तथा उसे सासन का जन्मवात अधिकारी होने की घोषणा की।

जमनी में इस प्रकार नाजी दल के नेता (भगूरर) हिटलर का अधिनायक्ल स्थापित हो गया था। सारी सत्ता उसके हाथां य केन्द्रित थी। नाजी दल के सत्ता में आने के प्रचास इंटली ने फासीवादी दल की सांति जमनी म सर्वाधिकारवादी राज्य की स्थापना की नायी। बीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर राज्य का नियं त्रण स्थापित कर दिया गया। नाजियां ने लोकत न का बहिष्यार कर दिया। जमनी में सभी विरोधी दला ने समाप्त कर दिशा गया। दिलीय विश्वयुद्ध के पूच एक्टलीय यदित सोवियत कस में भी स्थापित हो यंगी थी। 1948 ई में चीन मंत्री एक दल-साम्यवादी दल-की स्थापना हो बकी है।

i Jan G L

सोवियत रूस का साम्यवादी दल

^{50 &#}x27;Vanguard of the proletariat

जीवी यग द्वारा ही सम्मव है। सामाजिक परिवतन के बजानिक नियमों का इस जान्ति बारी वृद्धिजीवी वम को ही मली प्रकार सान होता है अत वही ऋत्ति सम्बंधी अपे-शित कदम जुरु सकता है।

हर म साम्यवादी दल दश का एकमात्र दल है। सविधान म साम्यवादी दल मो हो एनमात्र दल पोपित निया गया है एव सोवियत निर्वाचनों में केवल यही तल मार्रे संकता है। 88 थमिन वर्ग और महनतकदा लोगा के विभिन्न स्तरा के अत्यधिक संत्रिय एवं राजनीतिन रूप सं चेतन नागरिक रूस के साम्यवादी दल म सगठित होते हैं। यह (दल) समाजवादी प्रणाली क बेहनतकश लोगो को संगठित करते म अग्रगामी अमिका निमान क साय-साथ सभी प्रकार के सावजनिक एवं राज्य के सा-ठना का प्रमुख केंद्र है । ⁶⁸ सेनिन न साम्यवादी दस के दायित्वों को स्वस्ट करते हा पहा था "शासन गरने के लिए शांतिकारिया की एक सेना-सथय म दीक्षित साम्य-वादिया---वी आवश्यक्ता है। हमार पास साम्यवादी दल ऐसी ही सना है यदि दल की हटा दिया जाय तो ययाथ रूप में रूस में सबसारा वर्ग का अधिनायकत्व स्यापित नहीं हो सरगा ।'

मास्यवादी तस का सहदन

मास्यकाटी दल का सबहन विरामिडाकार है। सबसे निस्न तलीय और छोटी इकाई प्रारम्मिक दलीय संगठन है। उसके ऊपर कमश जिला एवं क्षेत्रीय दलीय सगठन हैं तथा सबस अवर राष्ट्रीय सगठन है। इनका विस्तत विवरण निम्नवत है प्रारम्भिक बलीय सगठन (प्रदस)-प्रारम्भ मे इ.ह सल (Cell) कहा जाता मा परन्तु अब प्रारम्मिक दलीय संगठन (प्रदम) की सन्ना दी जाती है। यह साम्यवादी दल की सबस छोटी सगठनात्मक इनाई है। प्रत्यक कारखाने, ग्राम, स्टोर, कार्यालय सामुदायिक कृषि फाम, विद्यालय, चिकित्सालय तथा गर-औद्योगिक प्रतिष्ठानो मे इस (प्रदस) नी स्थापना की जा सकती है। दल के कायकम म विश्वास रखने वाले एव उनका अनुगमन करने वाले किसी सस्या और प्रतिष्ठान मे कायरत कम से कम तीन सदस्य इसकी स्थापना कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, तीन सदस्या से इस प्राथमिक इकाई का गठन किया जा सकता है। लेकिन इस सख्या से कही अधिक सदस्य प्रारम्मिक दलीय सगठन में शामिल होते हैं। 1965 ई म 3,11,907 प्रार-म्मिक संगठन थे। 1946 ई में इनकी संख्या 2½ लाख थी। जिन प्रारम्मिक संगठना म 15 सदस्य होत हैं उनमं सात सदस्यों की एक कायकारिणी समिति होती है। इसे न्यूरो (Bureau) कहते हैं। प्रारम्भिक संगठन का प्रमुख सदस्य इसका मात्री होता

⁵¹ सोवियत सविधान, अनुच्छेद 141

⁵² सोवियत सविधान, अनुच्छेद 126

⁵³ Primary Party Organisation

है। इसका कायकाल एक वय होता है। जिन प्रारम्भिक सगठना की सदस्य सख्या 150 होती है उनमे वैतनिक मात्री नियुक्त किये जाते हैं जो पूरे समय तक दल का ही काय करते हैं।

प्रारम्भिक संगठनो द्वारा संगठनात्मक एव विरोध तथा प्रदेशन सम्व धी काय सम्मादित किये जाते है तथा नवीन सदस्यों की मर्ती एव उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। कारखानो एव सहकारी फर्मों के प्रारम्भिक संगठन उत्पादन के निर्धा-रित लक्ष्या को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं तथा श्रमिको में अनुशासन की स्थापना करते हैं। प्रारम्भिक संगठन के सदस्या का ही यह वायित्व है कि सदस्यों हारा दलीय कायक्म का उत्सवन नहीं किया जाता तथा दलीय निर्वेशानुसार ही काय सम्यादित किये जाते हैं।

जिला, प्रात्तीय या क्षेत्रीय स्तीय स्ताठन—प्रारम्मिक दलीय सगठन के ज्ञर शहर, प्रामीण क्षेत्र एव कृपक तथा औद्योगिक क्षेत्रों के दलीय सगठन होते हैं। इनके ज्ञर जिला और उनके ज्ञर प्रान्तीय या क्षेत्रीय दतीय सगठन होते हैं। प्रारम्मिक सगठनों के सदस्य अपने के उचर के दतीय सगठनों के सदस्यों एव प्रतिनिधियों को निर्वाचित करते हैं। शहरों और श्रान्तीय क्षेत्रों तथा दत्तीय सगठन और लेशियक क्षेत्रों ने सदस्या हारा प्रातीय दतीय सगठन के सदस्या को निर्वाचित किया जाता है। यहर, प्राम्य क्षेत्र, कृपक तथा औद्योगिक क्षेत्रों के सदस्या हारा प्रातीय दतीय सगठन के सदस्या का निर्वाचित किया जाता है। यहर, प्राम्य क्षेत्र, कृपक तथा औद्योगिक क्षेत्रों के दत्तीय सगठन की एक काय समिति होती हैं, जिसके अधिवेदान प्रति तीसरे माह होते हैं। इसके कई सचिव (Secretary) होते हैं। इनमें से एक 'प्रथम सचिव' कहताता है। इन सगठनों का काय अपने क्षेत्र के प्रारम्भिक सवीय सगठनों तथा गैर दत्तीय सगठनों (यथा—अमिक सवी, युक्क सप-ठनों एव सहकारी समितियों) के कार्यों का निरोक्षण एव पत्र प्रवस्त करना होता है।

प्रातीय सलीय सगठना के ऊपर विभाषीय, क्षेत्रीय या गणत प्रीय दलीय सग-ठन हाते हैं। 1966 ई के पूब इनकी बैठके प्रति इसरे दिन होती थीं। पर तु अब इनकी वठक प्रति चौथे वप होती है। स्तीय सम्मेलन द्वारा प्रातीय दलीय काय-समिति, चार सचिव एव विभागीय सगठन के लिए सदस्या को निवांचित किया जाता है। सभी सगठना के सदस्यों का निवंचन अप्रत्यक्ष रीति से होता है। 1962 ई के परचात प्रान्त मे दो प्रकार के सगठन हो गय हैं—एक के द्वारा कृषि तथा दूसरे के द्वारा औदोनिक हिंतो का निरोक्षण किया जाता है। प्रत्येक मणराज्य की दलीय कप्रिस होती है जो गणराज्य म दल का सर्वोच्च अग है।

स्रवित्त सपीय साम्यवावी कप्रित (All Union Congress)—उपर्युक्त दिनीय सगठना के ऊपर अखिल सपीय साम्यवादी कप्रित होती है। इसके सदस्यों को गण राज्या की दिनीय कप्रिता द्वारा चुना जाता है। पुराने दिनीय नियमा के अनुसार कप्रित का अपिवेदान प्रति तीन वय पश्चात होना चाहिए परन्तु 1952 ई के नवीन नियमा-नुसार कप्रित का अधिवेदान प्रति चीचे वय आयोजित किया जाता है। परतु इस नियम का अनिवार्यत पालन नहीं किया जाता है। पुराने नियमा के अधीन अखिल सपीय काँग्रेस के सन्त्रों के अन्तराल में दलीय सम्मेलन (Party Conference) आयोजित करने की व्यवस्था थी। 1939 ई से आगामी 15 वर्षों तक दल की काँग्रेस का कोई अधियेशन नहीं हुआ था। स्मरणीय है कि 1917 (काँग्रि) के परचात 1925 ई तक प्रति वय कांग्रेस के अधियेशन होते रहे थे। दलीय सम्मेलन (Party Conference) के अधियेशन प्रति वय काँग्रेस के अधियेशनों में ही आयोजित किये जाने की व्यवस्था है। सेकिन इस नियम का पूणक्षेय अनुगमन नहीं किया जाता। 1941 ई से दलीय सम्मेलन के अधियेशन ही नहीं हुए हैं। यह दलीय जीति से सम्बंधित तास्कालिक समस्याओ पर विचार करता है (दलीय नियम सरया 37)। 15

अखिल सधीय काग्रेस के अधिवेदान दीयकाल तक आयोजित नहीं होते हैं।
यद्यपि दलीय नियमों के अनुसार कांग्रेस द्वारा ही दल की नीति नियारित की जाती
है, तास्कालिक महत्व के प्रस्ता के सम्बच्ध में निजय क्येंग्रेस हैं। तथा दल की अग्रेस
समिति का चुनाव किया जाता है तिकन दलीय सत्ता का केंद्र कांग्रेस के अपन कहो
है। कांग्रेस का अधिवेशन सामाण्यत 15 दिन से अधिक नहीं चलता है।

केन्द्रीय समिति—यह दल का वर्षाधिक महत्वपूण अग है। इसके सदस्य अखिल सपीय काग्रेस द्वारा गुप्त मतदान की रीति से चुने जाते हैं। 1918 ई मे इसमे 15 सदस्य तथा 8 प्रत्याधी (Candidates) हुआ करते थे। सन् 1964 ई मे इसमे 15 सदस्य तथा 8 प्रत्याधी (Candidates) हुआ करते थे। सन् 1964 ई मे इसकी सदस्य-सख्या 71 थी। अब इसमे 133 पुण एव 122 वैकिटिफ सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त 68 वैकिटिफ सदस्य या प्रत्याधी होते थे। वप म के द्रीय समिति के 3 से 12 तक अधिवेशन होते थे। नवीन दसीय नियमा के अनुसार के द्रीय समिति के प्रति वप कम से कम दो अधिवेशन होने चाहिए। के द्रीय समिति सल्यान की नीति निर्धारित करती है। यह दक्षीय सगठन की घुरी है। के द्रीय समिति सस्यान के निर्वेशक का काम करती है। यह दक्षीय सगठन की घुरी है। के द्रीय समिति सस्यान के निर्वेशक का काम करती है। यह सहित स्वाराधिक सम्याक का स्वरा के सम्याक करती है। यह सामित दितीय सम्याक के सम्याक का कि सम्याक सम्याक के स्वरा सम्याक सम्याक सम्याक सम्याक सम्याक सम्याक सम्याक सम्याक सम्याक के स्वरा सम्याक सम्याक

दलीय के द्रीय समिति का आकार काफी वडा है। अत उसके द्वारा उप-

⁵⁴ Carter, Ranney and Hez The Government of the world Union, 1954 p 85

⁵⁵ Ibid, p 85
56 Refer to Party Rules (Article 367-quoted by Carter and others, op cit, p 85

समितियो एव अधिकारियो को काय सौंप दियं जात हैं। ने द्रीय समिति ना एक अध्यक्ष, एक महासचिव, अनेक सहायक सचिव तथा दो उप-समितियाँ होती हैं। इनम से एक उप समिति राजनीतिक समिति (Polithurcau) बहलाती है। यह व्यवहार म के द्रीय समिति स अधिक पक्तियाली है। 'ब द्रीय समिति सत्ता का अन्तिम अधिप्ठान नहीं है। 'इसके बहुत कम अधिवेशन होते हैं। यह आकार म पर्याप्त वही है। अत नीति-निर्धारण एव अपन दायित्वा के सम्पादन की हृष्टि से कदीय समिति अनुप-यक्त है। \$7

राजनीतिक समिति या बलीय प्रेसीडियम (Politburcau or Presidium of the Party)-दल की वास्तविक सत्ता राजनीतिक समिति म निहित होती है। इसका अध्यक्ष दल का महासचिव होता है । यह दल का सर्वाधिक शक्तिशाली सदस्य होता है। इसकी स्थापना दलीय काँग्रेस द्वारा 1919 ई म की गयी थी। यह समिति नीति सम्बाधी महत्वपूण विषया का निणय करती है। सभी महत्वपूण आर्थिक, राज-नीतिक, सामाजिक, आन्तरिक एव अन्तर्राष्ट्रीय समस्याजा का निवय समिति द्वारा किया जाता है। शासन के विमिन्न विमागा द्वारा समिति की प्रतिवेदन दिय जात हैं। इसके अधिवेशन गुप्त होत हैं। समिति बारा जिस रीति 🛮 निणय किय जात हैं उसम मतभेदां का नान होना सरल काय नहीं है। कुछ आलोचका ना कयन है कि समिति मे पर्याप्त बाद विवाद होता है। सदस्या म परस्पर मतभेद भी होते हैं। अ स्टालिन साम्यवादी दल का महामात्री था एव बहुत समय तक समिति का अध्यक्ष रहा था। वह राजनीतिक समिति के निणयों को प्रमावित करता था। "राजनीतिक समिति के वप मे प्रति सप्ताह अनेक सम्मेलन होते रहते हैं। इस समिति की अनक समितियाँ एव आयोग होत हैं, ये समितियाँ विभिन्न मामला की देखमाल करती हैं। राजनीतिक समिति सोवियत रूस म, ऑग के शब्दा में, नम्पूर्ण दलीय संगठन की जाधारशिला है। 60 यह सामृहिक निर्देशक है। यह के द्वीय समिति का के दीय तत्व है। यह दल म सत्ता का केवल के द्र ही नहीं है, इसके सदस्य भी स्थायी होते हैं। एक लम्बे समय तक स्टालिन एव उसके सहयोगियो का इस समिति पर अधिकार रहा था।⁶¹ सिद्धान्त मे राजनीतिक समिति के द्रीय समिति की उप समिति है। अखिल समीय काँग्रेस के अधीन होते हुए भी राजनीतिक समिति वास्तव म दल का सर्वोच्च अग है। राजनीतिक समिति समाजवादी व्यवस्था की समस्त झाखाओ का क्रियारमक निर्देशक है।

1952 ई मे 19वी दलीय वृद्धिस ने राजनीतिक समिति के स्थान पर प्रेसी

⁵⁷ Carter and thers op al p 86

⁵⁸ Ibid , pp 85 87

⁶⁰ Ogg and Zink Modern Fort on Governments, 1965, p 825 61 Carter and others op cst, p 81

दिसम की स्थानना की है। इसकी कुल सदस्य सक्या 36 है, जिसमे 25 पूण एव 11 वकित्यन सदस्य होते हैं। साम्यवादी दल के सदस्या के अतिरिक्त के द्वीय योजना आयोग क भी कुछ सदस्य प्रेसीडियम के सदस्य होते है लेकिन वास्तविक सत्ता प्रेसीडियम के 4 या 5 प्रमुख सदस्यों के हाथा म हो होती है। स्टालिन की मृत्यु के पश्चात प्रेसीडियम की सदस्य-मस्या की पटाकर 14 कर दिया गया है। इन 14 सदस्यों म 10 पूर्ण एव 4 अन्य सदस्य होते हैं। की

राजनीतिक समिति के अन्तिरिक्त स्त की के द्वीय समिति की एक समजन समिति (Orgburo) होती थी। इस समिति की स्थापना 1919 ई मे की गयी थी। लेकिन 1952 ई म इस समिति को समाप्त कर दिया गया है। राजनीतिक समिति एव सगजन समिति म दोई स्पष्ट काय विमाजन नहीं था। साम्यवादी वल के अधिकाश प्रभावसाती नेता इसके सदस्य हुआ करते थे लेकिन यह समिति राजनीतिक समिति सम महस्वपूर्ण थी। इस समिति के तदस्यों की सक्या 5 से 13 तक रही थी। धीरे पीरे दल का सिवास्त इस समिति के दायितों की सम्यादित करने लगा था। यह समिति दलीय सगजन एव कायपालिका सम्बाधी कार करती थी। धीरे सित्त समजन एव कायपालिका सम्बाधी कार करती थी। धीरे सित्त समजन एव कायपालिका सम्बाधी कार करती थी। धीरे

सिंघ्यासप—सिंववालय दल के कार्यों को सम्वास्तित करने वाला यास्तिकक निर्देशक यहम है। 1952 ई के नवीन दलीय नियमों के अनुसार महासिंदिव के स्थान पर सिंव्यालय म 10 सिंववा की नियुक्ति की गयी है। स्टालिन की मृत्यु के प्रमान यह सुद्धा घटालर 5 कर दो गयी है। स्मरणीय है कि 1922 ई ते कैकर अपनी मृत्यु तक स्टालिन ही महासिंदिव था और वह सिंव्यालय के कार्यों का नियान पत्र पत्र निर्देशक पा । सिंव्यालय सिंव्यालय सिंव्यालय सिंव्यालय के कार्यों का नियान के किए जस्तरालय में कार्यों का नियान के लिए जसरदायों है। यह अनेक अनुमागो एवं कार्यालयों में विभाजित है।

दल के क्षेत्रीय, जिलास्तरीय तथा स्थानीय संगठनों के अतिरिक्त सलग्न संगठन भी होते हैं। इन के नवयुवका के सगठन हैं। वे कोमसोमोल (Komsomol), पायनियर (Pioneers) एवं आक्टोजिस्ट (Octobrisis) के नाम से पुकारे चाते हैं। कोमसोमोल में 25 से 26 वप, पायमियर में 10 से 16 वप पृव ऑक्टोजिस्ट म 8 से 11 वप सक की आयु के युवक एवं बातक होते हैं। इन संगठना का काय चला के नव-युवको एवं वातक-वालिकाया की साम्यवादी मावना से विक्रित करना है। कोमसो मोला साम्यवादी क्षावादी दल वा महत्त्वपूष उपकरण है। इनके संदस्या की संख्या लाखा में होती है। 4

⁶² Ogg and Zink op cit, p 826 63 Carter and others op cit, p 87 and Ogg and Zink op cit, pp 825 826

⁶⁴ Carter and others op at , pp 89 90

साम्यवादी दल की सदस्यता

साम्यवादी दल के सगठन में विश्रेष सावधानी वरती जाती है। हर व्यक्ति साम्यवादी दल का सदस्य नहीं हो सकता, केवल दल म निष्ठा रखने वाले चुने हुए व्यक्तियों को ही सदस्य बनाया जाता है। दल के सिक्रय सदस्या की सख्या बहुत कर होती है। लेनिन का कथन था कि दल की "सदस्थता कम करके दल की शक्ति म वृद्धि कीजिए। 1922 ई मे लेनिन की यह खिकायत यी कि दल आकार मे वडा है और अवसरवादी तथा लोभी व्यक्ति उसम घस बाये हैं 165 साम्यवादी दल के नेता ब्रिटेन, फास या मारत के लोकता जिक दलों के नेताओं की माति विना किसी भेदमान के सभी व्यक्तिया को दल का सदस्य बनाने की नीति के विरोधी हैं। स्टालिन के अनुसार "प्रत्येक व्यक्ति दल का सदस्य नही हो सकता। इस दल की सदस्यता से सम्बर्धित कठिनाइयो एव अभावाता को भेलना हर व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं है। इस दल मे तो श्रमिक वग के पूत्रो, अभाव एव सघप मे पत्ती सत्तामी को ही सदस्यता दी जानी चाहिए ।"66 इस हिटकोण के पश्चात भी साम्यवादी दल की सदस्य-सख्या म विद्व हुई है। माच 1917 ई म इसकी सदस्य सख्या 23 हजार और नवस्वर 1917 मे 2 लाख थी। 1947 ई मे यह सख्या बढकर 6 लाख हो गयी। 1921-22 ई से करीब एक चौथाई सदस्यों को दल में से निष्कासित किया गया था। 1928-29 एव 1938-39 ई मे दल से बडे पैमाने पर सामूहिक निष्कासन (purge) हुए थे। इसके अतिरिक्त समय समय पर छोटे निष्कासन तो होते ही रहते हैं। 1939 ई के पुत्र कुछ विशिष्ट वन के व्यक्तियो पर दल की सदस्यता के सम्बुध में विशेष प्रतिवाध थे। वगभेद के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। स्मरणीय है कि बुर्जुंआ वर्ग एव पूजीपतियों में लिए साम्यवादी दल के दरवाजे वाद है। 1939 ई में दलीय सदस्यता सम्बाधी नियमो को सामा य बनाया गया था । नवीन सदस्यता के नामी की सिफारिश दल के ऐसे सदस्यों को करने का अधिकार दिया गया है जो स्वय तीन वप से दल के सदस्य हैं तथा एक वय से उस व्यक्ति से मली प्रकार परिचित्र हैं जिसका नाम वे सदस्यता के लिए प्रस्तावित करते हा । प्रत्येक व्यक्ति को बडे सीच विचार एवं दल म बाद विवाद तथा विचार विमर्श के पश्चात उसकी व्यक्तिगत योग्यता एवं नाल चलन के आधार पर मर्ती किया जाता है। लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान इस नियम को शिथिल कर दिया गया था। दल के बहुत से सदस्य युद्ध म भारे गयं थे अत इस अभाव की पूर्ति एव दल की स्थिति को सुदृढ करने के लिए यह आवश्यक था।

दल के नवीन सदस्या का दलीय सिद्धा ता एव कायकम मे राजनीतिक शिक्षा दी जाती है। दल मे अधिकाशत नवयुवक एव नवयुवितया ही होती है। द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरात दल के 63 6 प्रतिशत सदस्य 35 वप से कम आयु के थे। "

⁶⁵ Lenin as cited by Carter and others op cit, p 75 66 Stalin as quoted by Carter and others Ibid, p 75 67 Carter and others op cit, p 77

सोवियत साम्यवादी दल का अनुशासन

सोवियत साम्यवादी दल का अनुशासन फौलादी है। साम्यवादी दल द्वारा अपने समी विरोधिया का दमन किया जाता है। दल के अदर राजनीतिक बाद विवाद और निरोध को सिद्धा तत स्वीकार निया गया है। दलीय सगठन एव कावपद्धति सम्बाधी इस सिद्धा त को लोकता निक के द्रवाद (Democratic Centralism) की सजा दी जाती है। दलीय सगठन के सम्बाध में लोकतन्त्र को लेनिन एक निरथक एवं हानि-कारक खिलीना मानता था। उसने 1906 ई मे लोकता निक के द्वाद के सम्बन्ध में कहा था कि "इसका अब यह है कि सदस्या को आधोचना की स्वत त्रता तभी तक प्राप्त होगी जब तक उससे किसी काय की एकता समाप्त नही होती। दल की नीति एव काय को असम्मव बनाने एव उसे समाप्त करने वाली किसी जालीचना को स्वीकार नहीं किया जा सकता।" समयवादों दलीय सगठन में लोकत न का तत्व इस अप में विद्यमान है कि दल के सभी अधिकारी दलीय सदस्या द्वारा निर्वाचित होते हैं, उह मत देन का अधिकार होता है, नीति सम्बाधी प्रश्नो पर दलीय सदस्यो द्वारा बाद विवाद के परवात बहुमत के आधार पर निणय लिये जाते हैं। लोकत त यही तक सीमित है। " दलीय अनुसासन सनिक अनुशासा की मांति कठोर होता है। दल म सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर है। अल्पमत बहुमत के अधीन होता है और निम्न निकासो पर उच्च दलीय निकासो के निर्णस ब धनकारी होते हैं। निस्ने या अधीन दलीय इकाइमी को कोई स्वत वता प्राप्त नहीं होती है। दलीय नाति निर्पारण के समय सदस्यों को बाद विवाद की पूर्ण स्वत त्रता प्राप्त होती है पर तु सभी निणय बहुमत से होते हैं तथा एक बार निणय हो जाने के पश्चात दे सभी सदस्या पर समान रूप मे ब धनकारी होते हैं मले ही उनम से कुछ उससे सहमत न हो । लेनिन ने इसी सिद्धात के आधार पर रूसी साम्यवादी दल का सगठन किया था और वह अय देशा के साम्यवादी वलो के लिए एक उदाहरण बन गया है। स्मरणीय है कि मन्ति के प्रारम्भिक वर्षों से दलीय अनुशासन इतना कठोर नहीं था। उस समय दलीय अधि-वेशनो मे सदस्या को पर्याप्त स्वत त्रता रहती थी। 1918 ई म के द्रीय समिति न जमनी से सन्धि सम्ब वी लेनिन के प्रस्तावा की दो बार बस्वीकार किया था यद्यपि भात में वे बहुमत से स्वीकार कर लिये गय थे। मवीन वार्षिक नीति के अनुगमन के परचात दलीय अनुशासन के सम्बाध में विवाद उत्पन्न होन लगे थे। काटर ना मत है कि दलीय सदस्यों का प्राप्त विचार-स्वात ज्य का वर्ष यह नहीं था कि दलीय अनू-शासन किसी प्रकार शिथिल हो गया था। 1920 ई म लेनिन ने साम्यवादी दल के सनिक अनुशासन पर आभारित लौह-अनुशासन की अनिवायता पर चचा भी भी थी।

⁶⁸ Cited by Carter and others of ct, p 78
69 Refer to Article 19 of the Party Regulations (1939), cited by Carter 1bid, p 78

वह इसे फ़ार्ति एव गहयुद्ध-काल में ही नहीं अधित वग भेद की अवस्था में मी अपिर हाय एवं आवस्थक मानता था। लेगिन के पश्चात स्टालिन काल में भी दलीय अनु धासन लोकतानिक के द्रवाद पर ही आधारित रहा है। लोकत त्र का तत्व साम्यवादी दल के सगठन एवं कायपद्धति में गौण है, के द्रवाद का तत्व प्रधान एवं मुखर है। ⁰ समीक्षा

दल का सगठन स्तुपाकार है। सोवियत साम्यवादी दल एक विश्वास एव यात्र रचना दोना ही है। विश्वास इस अथ म है कि दल आर्थिक एव राजनीतिक सिद्धा तो का एक व्यापक निकाय है। इन सिद्धा तो म सभी सदस्य विश्वास करत हैं। साम्यवादी दल की सदस्यता में वह माबात्मकता निहित है जी धार्मिक सम्बंधा में होती है। दल यात्र रचना इस अथ में है कि एक व्यवस्थित मानव समूह अर्थात दल के सभी अगो पर निश्चित उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए केन्द्रकृत निय शण रखा जाता है। 11 दल के सिद्धात माक्स एव लेनिन के विचारी पर आधारित हैं। जुलियन टाउ स्टर के अनुसार सोवियत कुस म विधियो, आदेशो और सस्थाओं का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर हैं।⁷² साम्यवादी दल को सोवियत रूस का एकमान दल घोषत किया गया है⁷⁸ एवं श्रमिक वग तथा अय सभी नियाशील सोवियत नागरिकों को साम्य वादी दल में ही सगठित होने का अधिकार है। 1961 ई से सोवियन साम्यवादी दल को सोवियत जनता के अग्रमामी दस्त (Vanguard of the Soviet People) की सज्ञा दी जाने लगी है। साम्यवादी दल के मीतर दलवादी, विभिन्न मतमतान्तरी एवं मतभेदों के लिए कोई स्थान नहीं है। दलव दी एवं दल के उद्देश्यों के प्रति सहज खदासीनता असहय है। ऐसे सदस्यों को निष्कासन का दण्ड भोगना पडता है। साम्यवादी दल एकल, एकीकृत एव के द्वीभूत सगठन है। यह एक ठीस प्रस्तर शिला (Monolith) की तरह है। अत इस Monolithic दल कह सकते हैं। दल सोवियत रूस में सत्ता का केंद्र विद् है। इसे सम्पूण सोवियत समाज व शासन की धुरी कहना

⁷⁰ Merle Fainsod How Russia is Ruled, p 181 and Ogg and Zink Modren Foreign Governments, p 850

⁷¹ The communist party of the Soviet Union is both a creed and a mechanism. It is a creed in the sense that is cherishes an elabo rate body of economic and political dogmas to which all its members must unswervingly adhere. Membership in the party frequently involves an emotional relationship suggestive of a religious affiliation. It is a mechanism in the sense that it is grared in all of its parts to highly centralised control by a single compact group driving steadily toward an ultimate goal. —Harold Zink. Modern Governments. 1963. p. 573.

⁷² Julian Towster Political Power in the U S S R p 207

⁷³ Article 141, Constitution of U S S R

अधिक उपयुक्त है। यह शक्ति का के द्रीय अधिष्ठान स्थल है। स्टालिन अपनी मृत्यु-पयात सोवियत रूस का सर्वेसर्वा रहा था। 1956 ई की 20वी कांग्रेस म स रचेव ने निस्टालिनीकरण (Destalmisation) का सूत्रपात किया था। इसके फल-स्वरूप जो तथ्य प्रकाश में आये हैं उनके अनुसार नेता ही सब कुछ है। पार्टी स्टालिन के निर्देशों को मौन स्वीकृति दती रही थी। स्टालिन साम्यवादी दल का महामात्री था, यह दलीय राजनीतिक समिति का अध्यक्ष एव सोवियत रूस का प्रधानमन्त्री था। 1941 ई तक उसने कोई सरकारी पद स्वीकार नहीं किया या, फिर मी वह रूस का वास्तविक शासक था। साम्यवादी दल के महाम त्री के रूप मे वह सम्पूण शासन-स्यवस्था को तियात्रित करता था। उसकी मन्यु के पश्चात खुश्चेव महासचिव बने थे। कुछ वर्षों तक मेलिनकोव एव बुलगानिन भी प्रधानमात्री रहेथ पर तु इनके समय में भी वास्तविक सत्ता खु, भीव के हाथों में ही रही थी। खु, भीव के अनुसार स्टालिन ने अनेक निर्दोप व्यक्तियों को अपने मादेश पर गोली से उड़ा दिया था। बेरिया (गुप्त लुफिया पुलिम के अधिकारी) के द्वारा उसने आतक का राज्य स्थापित कर रखा था। स्टालिन एक तानाशाह से कम नही था। लेकिन इस प्रवृत्ति का उसके साथ अ त नही हुआ है। स्टालिन के पश्चात सीवियत रूस में सामूहिक नेतृत्व विकसित हुआ है। खुरुवेव भी सत्तारूढ होने पर सर्वेसर्वा वन गये थे। उसने भी सामूहिक नतृत्व के सिद्धात की उपेक्षा की थी। खु इचेंब को उसके विरोधिया ने 1964 ई मे पद से हटा दिया है। सोबियत साम्यवादी दल एव शासन में क्या सम्ब घ है ? यह कहना कठिन है

कि कहाँ बल समान्य एव कहाँ बाधन का प्रारम्म होता है। य स्टालिन के अनुसार सीवियत सम में किसी भी राजनीतिक या समयन सम्बन्ध प्राप्त को बिना दलीय निर्देश के हल नहीं किया जा सकता। दल प्रमुख भूमिका निमाना है। दल एव बासन में पनिष्ट सम्बन्ध है। श्रीपचारिक रूप में दासन ही नियम बनाता है, उह किया वित करता है, सेना का नियमण एव उद्योगा का प्रवास करता है पर सुवस्त के मान के स्वास को स्वास के स्वस के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वस के स्वास के स्वस के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वस

⁷⁴ Harold Zink Mordern Governments p 567

⁷⁵ Staim J Problems of Lemmus, (1954), p. 168
76 Harper and Thompson Government of the Soviet Union, (1950),

pp 58 59 77 Carter and others of cst, p 62

है। उसका सम्पूण देश पर नियंत्रण है। फाइनर के अनुसार साम्यवादी दल ऐसा सगठन नहीं है जिसका आधार लोकत न हो। यह अपने आप में अधिनायकवादी है एवं इसका रूप लोकता त्रिक के द्ववाद के नारे में छिएा हुआ है। विपित्तयकवादी है एवं इसका रूप लोकता त्रिक के द्ववाद के नारे में छिएा हुआ है। विपित्तय ते लोकता त्रिक साम्यवादी दल एक विचित्र बलोकता त्रीय सस्या प्रतीत होगी लेकिन जिनका साम्यवादियों को माति विद्वास है एवं जिनकी हिन्द में सामाजिक एवं आर्थिक परिवतन मुख्य हैं उन्हें आलोचना की स्वत नता और दल के अवद विरोध के अधिकार दिव अस्यत नहीं तो हुट्ट अवस्य प्रतीत होगे। विद्यास तर है सोवियत सम्य का वास्तविक शासक है एवं फाइनर के अब्दों में साम्यवादी दल का सविधान हों। सोवियत स्व का वास्तविक सामक है। क्षेत्र कर पर छाया हुआ है। दल न केवल शिखर पर नियागण करता है जिपलु वह प्रत्येक स्वर पर छाया हुआ है। दल काति का रक्षक, समाजवादी ब्यवस्था का प्रेरक, आदश्च एवं श्विक्त है, यह सूचना प्रतान करता है एवं दल ही शासक है। स्टालिन के खब्दों मं दल राज्य में सर्वोच्च निर्देशक साित है। है।

चीन का साम्यवादी दल

पान का साम्यवादी व्यवस्था को स्थापना तथा जनवादी सोकत त्रीय जाति से चीनी साम्यवादी व्यवस्था को स्थापना तथा जनवादी सोकत त्रीय जाति से चीनी साम्यवादी दल ने निर्णायक भूमिका निमाई है। चीन का साम्यवादी दल सीवि यत साम्यवादी दल का प्रतिरूप है। यह अपने देश के श्रमिको एव मेहनतकया वग का अप्रमामी दस्ता है एव इनके वग सगठन का सर्वोच्च रूप है। स्मरणीय है कि 1949 ई में चीनी साम्यवादी दल देश से ज्याग काई शेक के शासन को उखाड फंकने में सफल हुआ था। चीन में मानस्वाद लिनिवाद के आदर्शों पर आधारित समाजवादी या साम्यवादी समाज की स्थापना करना साम्यवादी दल का प्रमुख उद्देश्य है। मानस एवं लिनित के दिचार दल की नीतिया एव कार्यों का आधार है। चीन में मी सीवियत स्थापत की स्थापना करना साम्यवादी दल का आविव्य सम्यवादी दल की माति लोकता त्रिकं के द्वाद पर इस दल का सगठन एवं कायपदित आधारित है। सोवियत सिवात में साम्यवादी दल को उत्सेख किया गया है, पर तुं चीन के जनवादी गणत नीय सिवधान में साम्यवादी दल का उत्सेख किया गया है, पर तुं चीन के जनवादी गणत नीय सिवधान में साम्यवादी दल का कही उत्सेख नहीं किया गया है। सरस्था एवं सगठन

चीनी साम्यवादी दस की स्थापना सितम्बर 1920 ई मे श्रापाई म की गयी यी। जुताई 1921 म इसका पहुला सम्मेवन हुवा था। उस समय से निरन्तर इसकी सदस्य सक्या म वृद्धि होती रही है। 1951 ई म 58 लाख एव 1970 ई के दसक

⁷⁸ Finer The Governments of Greater European Powers, p 868

⁷⁹ Carter and others op cat, p 91

⁸⁰ Finer op cit, p 789

⁸¹ Refer to Carter and others op at, pp 66 72

में दल की सदस्यता 170 लाख थी। पर तु यह सध्या कुल देश की जनसंख्या की हिंदि से काफी कम है। प्रत्येक 18 वर्षीय या उससे अधिक आधु के व्यक्ति जो श्रम-जीवी होते हैं तथा दूसरा के श्रम का शोषण नहीं करते, साम्यवादी दल के सदस्य बन सकते हैं। सदस्यता के नये नामी का प्रस्ताव दल के दो पूण सदस्यो द्वारा किया जा सकता है। प्रारम्भ में उसे दल की अस्थायी सदस्यता प्रदान की जाती है। एक वय तक दलीय सिदातों से उसे प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती है। तत्पद्यात उसके राजनीतिक गुणा का सदमतापूचक श्रीकत्वन किया जाता है और उसके बाद ही वह दल का पूण सदस्य बनाया जाता है।

दल का समठन स्तूपाकार है। सबसे छोटे दलीय निकाय को सैल (Cell) कहते हैं। इनके द्वारा काउण्टिया एव नगरपालिकाओ की दलीय कांग्रेसो के लिए प्रति निधि चुन जात हैं एव काउण्टो तथा नगरपालिकाओ की काग्रवो द्वारा प्रातीय दलीय काँग्रेस के सदस्य निर्वाचित किय जाते हैं। सबसे खीध पर राष्ट्रीय दलीय सगठन है। दल का एक अध्यक्ष होता है।

राष्ट्रीय दलीय सगठन के निम्न अग होते हैं

(1) राष्ट्रीय दलीय काग्रेस,

(2) के द्वीय समिति।

राष्ट्रीय बसीय फाग्नेस—राष्ट्रीय वलीय काग्रेस के सदस्य प्रातीय वलीय कांग्रेसा द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। इसका कायकाल 5 वप है और इसकी सदस्य सब्या एक ह्लार से भी अधिक है। नियमानुसार प्रति वप इसका एक अधिवेदान अपे क्षित है। के द्रीय समिति विद्येष परिस्थितियों में अधियेदान की अनुमति को अस्त्रीकार कर सकती है। दसीय काग्रेस के निर्वाचित अधिवेदान हुए हैं। काग्रेस के कियत दी विकात वीस वर्षी म इसके केवल दो अधिवेदान हुए हैं। काग्रेस होता के द्रीय समिति का निर्वाचन किया जाता है और काग्रेस के सजावसान-काल में समिति द्वारा हो काग्रेस के समी कतब्या की सम्पादित किया वाता है।

के ब्रीय समिति— के द्रीय समिति में 196 सदस्य होते हैं। सिदान्तत राष्ट्रीय संतीय कांग्रेस द्वारा इसका निर्वाचन होता है परातु व्यवहार म दलीय राजनीतिक समिति (Politbureau) की सात सदस्यी स्थायी समिति के द्वारा इसका चयन किया जाता है। इस समिति म दल के प्रमुख नेता होते हैं। सत्य तो यह है कि सदस्या का ज्यान वीन के सर्वेसवा माओ त्से चुन या दो एक व्यय नेतालों जो के क्या प्रमुख निर्वाच होते हैं। सत्य नोतालों जो के क्या पर निष्पर होता है। इसके वय म दो बार अधिवधन होते हैं। इसकी सदस्य सख्या मी अधिक है। चलीय काप्रस के स्वावधान-काल म के द्वीय स्थिति दल का सर्वोच्च निर्वेशक निकात है। अत यह दल के सस्यूय कार्यों का निर्वेशन करती है, वेकिन के द्वीय समिति दलीय नीति का निर्वेश्य नहीं करती है। वय य इसके एक या दो अधिवशन होते हैं और वह भी केवस दो या तीन सप्ताह के लिए हों । अने क

सकटकालीन अवसरो पर के द्रीय सिमिति में अधिवेदानों को आहूत हो नहीं किया जाता है। 1962 ई म के द्रीय सिमिति का 10वाँ अधिवेदान हुआ था पर तु इस अधिवेदान म दलीय एव राष्ट्रीय विषयों पर विचार करने के लिए केवल चार दिन निर्धारित किये गये थे। सत्य तो यह है कि के द्रीय सिमिति नेताओं द्वारा पूव निर्धारित नीति पर प्रमुख वलीय नेताओं की प्रतिक्रिया नात करने का माध्यम है।

राजनीतिक समिति (Politburcau)— यह दत की प्रमुख समिति है एवं के द्वीय समिति का निर्देशक एवं नियं प्रण वि दु हैं। इसम 20 पूण एवं 6 वकिएक सदस्य होते हैं। इसके निर्णया को के द्वीय समिति को भेजा जाता है एवं वह उ हैं अनुमोदित करती है। इस समिति के द्वारा दलीय नीति निर्धारित की जाती है। विभिन्न के द्वीय समिति राजनीतिक समिति के विणया को केवल स्वीकृति देने वासी रवड की मोहर नहीं है। वास्तव म कं द्वीय समिति ही दलीय सविष्णान के अनुसार निणयों को वैधानिक रूप प्रदान करती है। राजनीतिक समिति की एक स्थायी समिति होती है। माओं सेते तुग, चाऊ एन लाई, वेन यान एवं निज पाओं के से नेता इसके सदस्य होते हैं। की वाओं घो भी इसने सदस्य हें थे। इस स्थायी समिति को राजनीतिक समिति का 'ज्ञानकोप' कह सक्ते हैं। यह समिति राप्ट्रीय दलीय नीति के निर्धारण में प्रमुख एवं निर्णायक भूमिका निजाती है। यह समिति राप्ट्रीय दलीय नीति के निर्धारण में प्रमुख एवं निर्णायक भूमिका निजाती है।

इसके अंतिरिक्त दल का एक सचिवालय होता है। यह दलीय कार्यालम के रूप में काय करता है। दलीय नियायण आयोग दल के नियमों के उल्लंघन एवं अनु-

शासन सम्बंधी प्रश्नों से सम्बंधित होता है।

लोकतास्त्रिक के दवाद

सीवियत साम्यवादी दल की मीित चीन के साम्यवादी दल के सगठन एव अनु श्वासन का आधार लोकतानिक के द्वाद है। चीन में 'के द्वाद' का तरन अधिक श्वासन का आधार लोकतानिक के द्वाद है। चीन में 'के द्वाद' का तरन अधिक श्वासन का आधार लोकतानिक है। मांगो तसे तुम के अनुसार चीनी राजनीतिक प्रवस्ता एक साथ लोकतानिक एव के दक्त है। चनवादी चीम के सविधान के अनुसार स्वीय सगठन में लोकतानिक प्रवास के सिद्धान के अनुसार के अनुसार की स्वीय सगठन में लोकतानिक के द्वाद के सिद्धान को मायता दी गंगी है। सिष्धान के अनुच्छेद 2 के अनुसार 'राष्ट्रीय जनवादी चीयत, स्थानीय जनवादी कीमितो एवं राज्य-सगठनों में लोकतानिक के द्वाद का अनुसमन किया जाता है। दलीय काय पद्धित के अनुसार निष्य सेने के पूर्व दलीय सदस्या को विचार विसंद एवं आलीचना का अधिकार होता है। नीति के निर्धारित हो जाने के पद्यात उसे नियानित करना प्रत्येक सदस्य का दायित्व है तथा वहुमत के निष्य अत्यमत पर ययनकारी होते है। सत्ता ना प्रवाह उत्तर से नीचे की ओर होता है। यही लोकतानिक के देवाद है। सत्ता ना प्रवाह उत्तर से नीचे की ओर होता है। दलीय अनुसासन फीलायी होता है। समुण समाज एवं सावत पर साम्यवादी दल के पर्लाम का एका शिवार है। यत होता है। समुण समाज एवं सावत पर साम्यवादी दल का एका शिवार है। वत एवं पासन म कोई विमाजक रहा गही है। दल के सभी महत्वपूष नेता शासन के उच्च पराधिवारी होत हैं। धामकीय अभिकरणा म साम्यवादी दल की साखाए स्थापित की जाती हैं तथा समय सभय पर धासन की आ तरिक नीति के सम्बन्ध म दलीम निर्देश दिय जात हैं। जनवादी किसेस की स्थापी सिमिति को सिवधान द्वारा शासन के कामों कि निर्देश पर अधिकार दिया गया है तथा धासन के सभी स्तर के कामों एव निणयों का रहे या सप्ताधित करन ना उसे अधिकार है। उस देश में समस्त विरोधी दला एवं भानित विरोधी दिला एवं भानित विरोधी सित्य सा सप्ताधित करन ना उसे अधिकार है। उस देश में समस्त विरोधी दला एवं भानित विरोधी सित्य सा सकामा करने ना अधिकार है (अनुक्षेत्र 19)। भीनी साम्यवादी दल पास्तव म चीनी जनवादी प्रणाज्य की राजनीतिक सत्ता का अतिम स्रोत है। सना य धासन पर उसका पूण नियम्त्रण है। सदस्यों की समय समय पर ए। हानी होती रहती है।

वीनी साम्यवादी दक्ष म भी गुटबन्दी है। एक गुट का तेतुत्व चाऊ एन लाई, तो इसर ना भी दाओ वी करत रहे हैं। मान्नी रते तुन के नेतत्व एव उसकी उपस्थिति क नारण य विवाद सुनकर सामन नहीं आ रहे हैं। साम्यवादी चीन म पिचमी मैसका से अनुसार दलीम अधिनायकवाद है। स्वत तता अस्पिषक सीमित है। फाइनर के निम्म पान्य जो उन्होंने सोवियत साम्यवादी दल के सम्बन्ध में कहे हैं, चीनी साम्यवादी दल के सम्बन्ध में कहे हैं, चीनी साम्यवादी दल के सम्बन्ध में कहे हैं, चीनी साम्यवादी दल का सविधान देश (चीन) का वास्त-विक सविधान है।" चीनी साम्यवादी दल ही चीनी जनवादी यायराज्य का वास्तिविक सामक है। दल म मानो से तुन की विधात के हीय है एव स्टालिन ची मीति जनवादी चीन म मानो सा तुन का निजी अधिनायकत्व है।

यूगोस्लाविया मे दलीय पढित

पूर्योस्लाविया ना एकमान दल साम्यवादी दल है। 1952 ई मं पूर्योस्ला विया के साम्यवादी दल की 6वी काग्रेस ने दल का नाम बरत कर साम्यवादियां की लीग (League of the Communiste of Yugoslavia) रख दिवा है। इसके अतिरिक्त फरवरी 1953 इ म सेवालिस्ट एलाय स (Socialist Alliance) नामक एक अन्य सगठन का निर्माण किया गया है। सोवालिस्ट एलाय स तथा साम्यवादी लीग म पास्त्यरिक पिनट्ट सम्पक एव सहयोग है। शुक्रक एव स्वयंत्र सगठन होते हुए भी दोना के उद्देश्य समान है। साम्यवादी लीग का प्रधान चदय सद्धात्तिक नेतत्व एव राजनीतिक शिक्षा का काय करना है वबिक 'एवाय स' समाज के विशिष्ट राजनीतिक एव सामाजिक प्रश्तो से सम्बच्धित है। सामाय नीतियों का निर्पारण साम्य वादी लीग करती है। विधिष्ट स्थितियों में इस निर्पारित नीति नो क्रियादित करना सोशाविस्ट एलाय स का माय है। तीन ये केवल साम्यवादी विवारपारा ने हा सदस्य होते हैं विशिष्ट एलाय स में सिक्रय साम्यवादियों के बितिरक्त उनके समयक ऐव उनके सोगवस्तर भहण करने वाले सभी व्यक्ति एय सगठन धामिन होते हैं।

साम्यवादी लीग

यूगोस्लाविया की साम्यवादी लीग का संगठन रूस आदि आय साम्यवादी देशों के साम्यवादी दलों की माँति ही है । लोकता त्रिक के द्रीकरण के सिद्धान्त पर लीग का भी सगठन आधारित है। लोकतानिक के द्रीकरण के अनुसार दल के सदस्यों को विचार-विमश्च की स्वत त्रता होते हुए भी एक बार दलीय नीति के सम्बाध में निणय हो जाने पर उसको त्रियाचित करना दल के प्रत्यक सदस्य का कतव्य होता है । सोवियत साम्यवादी दल की माँति दलीय अनुशासन फौलादी होता है । दलीय नेताओं का दल पर पण नियात्रण होता है। लीग की सरचना आय साम्यवादी दली की माति एक पिरामिड के समान है। सत्ता का स्रोत ऊपर से नीचे की ओर है। दलीय सगठन के शीप पर दल के प्रमुख नेता होते हैं, जिनमें माशल टीटो का नाम प्रमुख है । साम्यवादी दल ने समाजवादी कार्ति की सफलता एवं फासिस्ट शक्तिया के विरुद्ध सफलतापुवक सथप किया है एव महत्वपुण भूमिका निमाई है । यूगोस्ला विया मे माशल टीटो का एक विशेष स्थान है। उन्हें अधिनायक नहीं कहा जा सकता और न वे सबैधानिक अध्यक्ष मात्र ही हैं। उनकी स्थिति इन दोनों के मध्य नी है। साम्यवादी लीग मे उनका प्रमुख स्थान है, वे दल के प्रमुख नेता हैं, साम्यवादी लीग की कायकारिणी के अध्यक्ष हैं। दल म सहद स्थिति तथा राष्ट्रनायक के रूप म प्राप्त लोकप्रियता के कारण उनकी स्थिति असाधारण रूप से सुद्देव हो गयी है। वे युगोस्लाविया के सबमान्य नेता हैं।

साम्यवादी लीग अतर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे समाजवादी अन्तर्राष्ट्रीय सगठन से सम्बिधत है तथा उसने सभी समाजवादी आ दोलनो का समयन किया है। देश में समी साम्राज्य विरोधों, प्रगतिशील एव लोकता निक दली और आ दोलनो तथा अप्य साम्यवादी समयक सगठनो एव अभिक सगठनो स साम्यवादी सीग सहयोग करती है।

रतीय समठन के तल पर साम्यवादी वल की छोटी छोटी इकाइमा—सैल (Cell)—हैं। प्रत्येक उत्तम, ग्राम एव सेना की टुकडियो म साम्यवादी लीग के ये आवारभूत समठन—सल—पाये जाते है। इनके ऊपर कम्यून, नगर, जिला, प्रात्त घा प्रदेशो एव जनवादी गणत नो के स्तरो पर साम्यवादी वल के समठन है। सबसे घीष पर 'वल का राष्ट्रीय समठन' है। प्रत्येक स्तर पर साम्यवादी लीग की कोंग्रेस एव कायकारिणी परिपद या के द्रीय समिति होती है। सल से सम्बर्धित पत समी सदस्यो की केवल सामा य समाएँ होती हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर साम्यवादी लीग का सर्वोच्च जग 'लीग की काँग्रेस' है। इसका कायकाल चार वय है। इसके द्वारा लीग की नीतिया, विधान, कार्यश्रम निर्घा रित एव स्वीकृत किये जाते हैं तथा के द्वीय समिति के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। दल की के द्वीय समिति दस की कायपालिका होती है। इसके द्वारा दल की नीति को रूपरेता तैयार की जाती है और वह काँग्रेस के समक्ष विचार एवं स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाती है। इसके अतिरिक्त समिति विभिन्न महत्वपूण राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याया का अध्ययन करती है। कंद्रीय समिति दलीय विकास के लिए सदद प्रयत्नधील रहती है। दसके एक प्रेसीडियम होती है। इसके अध्यक्ष के लिए सदद प्रयत्नधील रहती है। दस की एक प्रेसीडियम होती है। इसके अध्यक्ष को सचिव कहा जाता है। साम्यवादी लीग के अध्यक्ष, प्रेसीडियम व कार्य कारिया सिति एवं उसके अध्यक्ष को सीविव कहा जाता है।

साम्यवादी लीग के विमिन्न स्तरों के विश्वीय निकाय सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। सभी निकाया द्वारा निजय बहुमत से लिय जाते हैं। दल के विभिन्न पदो पर कोई सदस्य एक साथ दो बार से अधिक काल के लिए निर्वाचित नहीं हो तकता है। इसका उल्लंघन अपबाद ही है। साम्यवादी लीग के सदस्य शासन के विभिन्न सगठनों एवं सामाजिक सस्याओं से सिक्त रूप से सम्बंधित होते हैं, वे शासन के विभागों का मागदान करते हैं। वत यूगोस्लाविया में दल एवं शासन म कोई विमाजक रेखा नहीं है।

सोशलिस्ट एलाय सं

समाजवादी एलायन्स एक विशिष्ट प्रकार का ऐसा फारम है जहाँ विरोधी विचारा के ध्यक्तिया से विचार विमश सम्मव होता है। यह यूगोस्लाविया की स्वज्ञासन पद्धति का सस्यागत रूप है। प्रत्येक नागरिक को अपने प्रस्ताव रखने एव अपने विचार ध्यक्त करन के अवसर होते हैं। यह सगठन देश मे समाजवादी आदश की हप्टि से प्रगतिशील विचारों का प्रचार एवं काय करता है। इसके द्वारा थम करने वाले सभी पूरपो एव स्त्रियो को एकता के सूत्र मे आबद्ध कर दिया गया है। 18 वय ॥ अधिक अधु का यूगोस्लाविया का प्रत्यक निवासी इसका सदस्य होता है। एलाम स की स्थापना का आधार सैद्धातिक है अर्थात् देश में समाजनाद की स्थापनाथ समाज के विभिन्न क्षेत्रों में स्वदासन एवं लोकत त की स्थापना आवश्यक है। इसी प्रकार उत्पादन मे श्रमिको का सित्रय योग वाछनीय है। ग्रामीण क्षेत्रों मे कृपि सहकारी फार्मों की लोकतात्रिक आधार पर स्थापना समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए आवश्यक है। गप्ट्रीय स्तर की अपेक्षा सोश्रलिस्ट एलाय सं की गणत न, प्रात, जिले, नगर एवं कम्यून स्तर पर संगठनात्मक इकाइया पायी जाती हैं। प्रत्येक उद्यम, ग्राम एव मेना की टुकडियों में भी आधारभूत इनाइयाँ होती हैं। इनका सगठन भी साम्यवादी लीग की माति ही है। राष्ट्रीय स्तर पर एलाय स का सर्वोज्च अग 'एलायन्स की काग्रेस' है ।

साम्पवादी लीग एव एलाय स मे घनिष्ठ सहयोग एव सम्पक है। एलाय स के कार्यों का निर्देशन व्यवहार य सीग द्वारा ही किया जाता है। एलायन्स सामाजिक

⁸² The Socialist Alliance of Working People of Yugoslavia

1044 | आधुनिक शासनन न

एव आर्थिक क्षेत्र में साम्यवादी लीग का सिक्रिय अग है । दोनो ही संगठनो में माशल टीटो का प्रमुख स्थान है। स्पष्ट है कि साम्यवादी लीग यूगोस्लाविया मे सोवियत साम्यवादी दल की प्रतिमूर्ति है। माशल टीटो सम्पूण देश के शासन एव दलीय ब्यवस्था की धुरी हैं। किसी स्तर पर कोई भी निषय विना दलीय नेतत्व के नही किया जाता है। परातु यूगोस्लाविया म सोवियत रूस अथवा साम्यवादी चीन की सी कटटरता का अभाव है। कॉमिनफाम के प्रश्न को लेकर उत्पन विवाद के फलस्वरूप युगोस्लाविया ने स्टालिनकालीन सोवियत रूस का अधानुकरण करने से इकार कर दिया था। इस निर्मीक कदम के लिए माशल टीटो का व्यक्तित्व एव इध्टिकोण उत्तर दायी है। माशल टीटो का समाजवादी आ दोलन म प्रमुख एव महत्वपूण योगदान यह सिद्धात है कि प्रत्येक देश को अपनी परिस्थितिया के अनुरूप समाजवाद की स्थापना ना प्रयत्न करना चाहिए। उन्ह प्रमुख साम्यवादी देशों की पूछ से वैंधकर उपनिवेशा की माति उनके इशारो पर नहीं नाचना चाहिए। कामिनफाम सम्बधी

विवाद के फलस्वरूप यूगोस्लाविया म नवीन चेतना उत्पान हुई थी। वहाँ विकासी करण एव लोक्त न की दिशा म नवीन एव मौलिक प्रयोग हो रह हैं।

राजनीतिक दल ' बहुदलीय पद्धति [POLITICAL PARTIES (II)]

कुछ देशों म दो या एक दल के स्थात पर देश की राजनीति में अनेक दल या छाटे छोटे राजनीतिक गुट सक्रिय होते हैं। इस दलीय स्थित को बहुदलीय पद्धति कहते हैं। फास एव भारत इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। बहुदलीय पद्धति प्रधान देशों में अपेक्षाकृत राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त रहती है। ससदीय व्यवस्था वाले देशो मे किसी दल का स्पष्ट बहुमत न होने पर बहुदलीय व्यवस्था के अधीन मिश्चित मित्र-मण्डलो का निर्माण होता है। विभिन्न दल मंत्री पदी के लिए आपस में सौदेवाजी करते है । दलीय अनुषासन शिथिल या समाप्त हा जाता है तथा सदस्या की ध्यक्तिगत महत्वाकाक्षाओ पर कोई अकृत नही रहता । मिश्रित मन्त्रिमण्डलो की स्थिति कमजोर होती है। प्रधान मानी शासन का नेतत्व नहीं कर पाता । ऐसी स्थिति म बहधा विभिन दला के नेताओं को मिलाकर समावय समितियों का निर्माण कर लिया जाता है। यह समावय समितियाँ शासन की नीतियो पर विचार एव निणय करती हैं और बाद में मिनमण्डल इन निणयों का केवल स्वीकृति प्रदान कर देता है। यह मिन-मण्डलीय उत्तरहायित्व के तिद्धान्त का निषेध है । बहुदलीय पद्धि म मित्रमण्डला का अल्प कायकाल होता है। कायपालिका दुवल हो जाती है तथा अल्पसन्यक सदस्या या समूहो को अपन अनुपात से अधिक शक्ति प्राप्त हो जाती है और दूरगामी नीतिया एव योजनाओं का निर्माण सम्भव नहीं हो पाता है। मिश्रित झासन होने के नारण उत्तरदायित्व को निश्चित एव निर्धारित करना कठिन हो जाता है। बहुदलील पद्धति में जनता को प्रत्यक्ष रूप से शासन चुनने के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, न वकत्पिक शासन के दायित्वों को वहन करने योग्य उत्तरदायी एवं शक्तिशाली विरोधी दल का निर्माण ही सम्भव होता हैं। कुछ विद्वान इन दोषों के होत हुए भी बहुदलीय पद्धति के गुणा का उल्लेख करते हैं। वे निम्नवत हैं

(1) बहुदलीय पढ़ित स्वामाविक है। सम्पूण समाज को हम क्वेत दो वर्गो या विचारपाराजों में ही वर्गीकृत नहीं कर सकते जल विमिन्न विचारा की अनिव्यक्ति बहुदलीय पद्धति में ही सम्भव है। इस दलीय व्यवस्था के अधीन ही विधानमण्डल में सभी विचारों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकता है।

(2) मतदाताओ द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव करने का क्षेत्र वहुदलीय पद्धति

मे अत्यधिक विस्तृत हो जाता है।

(3) बहुदलीय पढित में शासन के निरकुश होने की अपेक्षाकृत कम सम्मा-बना होती है। शासन के लिए विरोधियों के अेप्ठ सुम्माना की उपेक्षा करना सरल या सम्मव नहीं होता है।

लास्की की दृष्टि में बहुदधीय पद्धति की अपेक्षा द्विदलीय पद्धति की अप्ठता का कारण यह है कि द्विदलीय पद्धति के अत्तमत निर्वाचन के समय जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन को चन सकती है 1⁸

फ्रांस की दलीय व्यवस्था

फास में बहुदलीय पद्धति है। स्मरणीय है कि किसी देश की राजनीतिक दलीय व्यवस्था और उसके विधायी तथा कायपासक सगठनों में परस्पर चिनष्ठ सम्बधि होते हैं। फास की राजनीतिक दलीय व्यवस्था का प्रमाव सम्यूण शासनत प्रपर पड़ा है। फेच दलीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ निम्नवत है

(1) प्राप्त में दल वडी सख्या में हैं। सामा यद प्रत्यक निर्वाचन में विभिन्न स्थानीय समूहों के अतिरिक्त 20 राष्ट्रीय दल माग लेते हैं। तृतीय गणराज्य-काल में चेम्बर सदन में प्रमुख दला की सख्या करीब 20 थी, चतुर्य गणराज्य में यह सख्या

12 थी। पाँचवे गणत न के विधानमण्डल म केवल आठ प्रमुख दल हैं।

(2) फ़ॅच दलीय व्यवस्था म स्थिरता का अभाव है। दलो का निर्माण एव विघटन वही तीव्रता से होता रहता है।

(3) दला का सगठन अपेक्षाकृत शिषिल होता है। वामपक्षीय दल सुसगठित हैं लेकिन दक्षिणपक्षीय दली—उप्रवादी एव स्वत न दल—के सगठन शिषिल हैं। साम्यवादी एव समाजवादी दली में सगठन सुदृढ़ हैं, इनकी नीतियाँ दलीय कपिस शिष्टारा निम्चित की आती हैं, इन दली को जन समयन प्राप्त है, यह दल अपने सिद्धान्तों को अधिक सहत्व देते हैं तथा सदस्यों को अनुवासनहोनता के लिए निम्कासन का वण्ड दिया जाता है। दिशाणप्रवीय दला म अनुवासन का समाव है, फलस्क्प ततीय एव चतुय गणराज्या म मित्रमण्डती के शीधाता से उत्यान एव पतन होते रहे हैं।

(4) फ्रेंच दलो म अनुधासित स्थानीय एव राष्ट्रीय सगठनो का अमान होता है। ब्रिटेन, अमेरिका एव भारत के दला की भौति उनके निष्चत दलीय कायक्रम नहीं होते हैं और न दलीय सामान्य सिद्धान्त ही होते हैं जो सदस्यों को एकता के सूप में आयद रखें। फांस के दला के नसदीय एवं सगठनात्मक पक्षा मं भी पूण सहयोग

¹ Lasks A Grammar of Politics, p 314

नहीं पाया जाता है। दल के राष्ट्रीय सगठनों का ससदीय पक्ष पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, अपितु प्रत्येक दल की ससदीय भाषा का यह दायित्व है कि वह मतदाताओं को दिये गये चननों के पालन हेतु ससदीय सगठन को व्यवस्थित रखें। केवल वाम-पक्षीय दलों के ही स्थानीय सगठन होते हैं। श्रेप दलों का कोई स्थानीय आधार नहीं हैं। निर्वाचन-काल में स्थानीय दलीय इकाइयों द्वारा प्रत्याशियों के चयन कीन तो दल की राष्ट्रीय समिति द्वारा नियन्ति किया जाता है और न ही राष्ट्रीय समा में उनके द्वारा दलीय सदस्यों पर बिटेन आदि देशों की माति अनुधासन रखा जाता है। यह मी आवश्यक मही है कि जो सदस्य जिस दल की टिकट पर चुना गया है वह उसी दल के सदस्यों का साथ दे। यह भी सन्मव है कि खंदस्य नवीन दल का गठन कर ले या किसी अप्य दल में सिम्मतित हो आयें।

फास मे वहुदलीय व्यवस्था तथा उसकी अस्यिरता के कई कारण है। उनमे प्रमुख निम्नवत हैं

- (1) फ़ास थे बहुदलीय व्यवस्था फ़ेच इतिहास की देन है। प्रत्येक शासन के परचात उसके कुछ अनुवाबी एव सम्बन्धित परम्पराएँ रह बाती थी। धीरे-धीरे ये दल के रूप में सगठित होते गये। फ़ेच ऋति से बहुदलीय पदित का प्रारम्म हुआ है। शान्ति-काल में फ़ास में यावा-त्रीय एव राजत त्रीय दो वय वन गये थे। गणत त्र की स्वापना के बाद राजत त्रीय वंग तीत समूहों में एव गणत त्रीय वंग दो समूहा में विमालित हो गये थे।
- (2) औद्योगिक विकास ने उपेक्षित एव शोपित सवहारा वग को जम दिया, फलस्वरूप समाजवादी दलो की स्थापना हुई। फास मे 1905 ई म समाजवादी दल तथा 1920 ई म साम्यवादी दल का उदय हुआ था।
- (3) धम ने भी फास में बहुबलीय पद्धति के विकास में योग दिया है। राज्य एवं चच के मध्य सम्बाधा को लेकर फैच समाज आपस में विभाजित हो गया था। कैयोजिक सम्प्रदायवादी उग्र, सामाय एवं पादरी विरोधी समुदाया म बँट गये थे।
- (4) फ्रेच जनता स्वभाव से व्यक्तिवादी एव स्वत त्रवापिय है। यह भी फाउ में बहुदलीय पद्धति के विकास का एक कारण है। फ्रेंच सतदाता अब यह अनुमव करत हैं कि कोई दल उनके विचारों का मली प्रकार प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है तो नवीन दल का निर्माण करने में उन्हें कोई विलाख नहीं होता है।
- (5) कुछ सबैधानिक व्यवस्थाओं ने भी बहुदसीय पदित के विकास म योग दिया है, उदाहरण के लिए—केम्बर ऑफ डेयुटीज (निम्न सदन) का कायकाल निष्यत होता था और बहु अपने चार वर्षीय केमकाल के पूब विषटित नहीं किया जा सनता था। मात्रमण्डल द्वारा ब्रिटेन की साति वेम्बर ऑफ डेयुटीज को मन नरने की मांग नहीं की जा सकती थी। इस व्यवस्था का यह दुष्परिचास हुआ कि मिण्णप्टस दित्त हीन ही गया और विजिन्न छोटेन्छीटे देशों को दासन को उखाड फॅकने मी गांकि हीन हो गया और विजिन्न छोटेन्छीटे देशों को दासन को उखाड फॅकने मी गांकि

प्राप्त हो गयी । फलस्वरूप फ्रेच राजनीति मे दलीय समूहो का श्रीध्रतापूवक निर्माण हुआ है ।

फा-स के प्रमुख राजनीतिक दल

फास मे निम्नलिखित राजनीतिक दल हैं

साम्यवादी दल-इसकी स्थापना 1920 ई मे हुई थी। इसकी सदस्य सस्या मं तीव गित से बिंद्ध होती रही है और 1947 ई मे इसके 10 लाख सदस्य थे। श्रमिक-मधो पर इसका एकाधिपस्य है। यह वतमान पूँचीवादी व्यवस्था के विरुद्ध है और मामसवाद लेमिनवाद के सिद्धाता में विश्वास करता है। उत्पादन के साधनी पर सामृहिक स्वामित्य का पक्षपाती है। विश्वेस नीति मे यह दल सोवियत सच से मैत्री का सम्पन्न तथा नाटो सगठन की सदस्यता का विरोधी है। इस ने अस्जीरिया के राष्ट्रवादी विरोधियों से वार्ती का समयन किया था।

दल का सगठन लोकता निक के द्वीकरण पर आधारित है। महाम नी दल का सबसे महत्वपूण पदाधिकारी है। राजनीतिक समिति दल का सबोंच्च अग है। दलीय अनुशासन कठोर है। 1924-28 ई में घेम्बर सदन के निर्वाचनों में दल को केवल 12 स्थान मिले थे। 1936 ई में इनको सस्या 30 हो गयी थी। 1946 ई की सिंघान समा में 159 तथा 1951 ई की राष्ट्रीय समा में 103 सदस्य में । चतुर्य गणराज्य-काल म यह सबसे अधिक समिठत और अनुशासित दल था। 1956 ई में विभाल के उत्थान के काण्य इस दल का प्रभाव कम हो यथा और राष्ट्रीय समा म सक्ष सबसे अधिक समिठत और अनुशासित दल था। 1956 ई में विभाल के उत्थान के काण्य इस दल का प्रभाव कम हो यथा और राष्ट्रीय समा म इसके केवल 10 सदस्य रह यथे हैं।

समाजवादी दल (The Socialist Party)—फान्स का समाजवादी दल जिटिश श्रम दल की प्रतिमूर्ति है। इसकी स्थापना 1879 ई में हुई थी। 1905 ई म इसका नाम समुक्त समाजवादी दल रख दिया गया। इसके पूव तक इसे श्राप्त रिष्ट्रिय श्रमिक सम की फ्रेच शाखा (S F I O) के नाम से पुकारा जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के पूव फेच राजनीति में यह सबसे बदा दल था। केंकिन इस लक्त को ब्रालिश्क मतभेदो से धर्वाधिक हानि हुई है। 1920 ई म उपवादी सदस्य दल से पुषक हो गये, फलरवरूप यह दल काफी कमजोर हो गया। द्वितीय विश्व-युद्ध के प्रारम्म के पदचात दल वुरी तरह विभाजित हो गया था। तत्कालीन सदस्य जून 1940 ई की पराजय, विज्वी (Vichy) शासन बादि प्रस्तो पर विभिन्न मत रखते थे। केंकिन तियोग क्ल्म एव वि सेट ओरियल जैसे कुछ दलीय नेता सर्वेच ही राष्ट्र एवं गणतात्र के मक्त वने रहे तथा नाजियों का विरोध करने के लिए राष्ट्र को प्रेरित करते रहे। उन्होंने पेता को शासन देने का विरोध किया था। इसके विपरीत दल म एक वन ऐसा या जो शान्ति को शायनिकता देने का समयक एव युद्ध का विरोधी था।

द्वितीय विश्व-युद्ध के परचात भी दला म विभेद बने रहे । समाजवादी दल शान्तिवादी एव शमिक सघवादी, विकासवादी एव उन्नवादी, चच एव साम्य- यादिया के पक्षधरों में विमाजित है अर्थात् उसमं विमित पक्ष एव प्रवृत्तिया पायों जाती हैं। दल की एक वढी कमजोरी यह रही है कि यह दल ब्रिटिश श्रम दल की मौति सदैव से श्रमिको का पक्षधर नहीं रहा है। सिद्धा तत समाजवादी दल मानस-वादी विचारधारा से प्रमावित है, वस सघप वामा काित के सिद्धा ता म विस्वास करता है, पर तु व्यवहार में दल की नीतियाँ विकासवादी समाजवादियों के सिद्धा तो पर आधारित हैं। सिद्धा तए क व्यवहार में यह भेद उसकी कमजोरी का एक श्रम कारण है, देश में वामपक्षीय साम्यवादी दल की उपस्थित से उसकी स्थित पर विपर्ति प्रमाव पडा है। शिक्षको एव स्वेत कालर मध्यमवर्गीय जनता तथा उत्तरी कास मश्रमिक जनता पर समाजवादी दल का व्यापक प्रमाव है। इस दल ने सीनेट के उन्नू लन का समयन किया था। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा, राज्य एकाधिकार की पृद्धि, श्रमिक विधियों, कृषि श्रमिकों, कास्तकारों एव छोटे स्वामियों के हिताय कृषि-सुधारों का मी दल ने उस समयन किया है। उस वामपियों के अलावा दल के होय सदस्य साम्यवादियों से मिलने के पक्षपती नहीं हैं ।

काटर एव हेज के अनुसार समाजवादी दल का सगठन साम्यवादी दल से अत्यिक्त मिन है। कायपद्धित की हिन्द से दोनों में कोई समता नहीं है। दलीय सगठन के प्रत्येक स्तर पर मतभेद और मुटव दी व्याप्त है। दलीय नेतावा को अपने दल के पूण समयन की कोई आधा नहीं होती है। दल के सगठन और ससदीय पक्ष के सम्बन्ध विवाद का विषय रहे हैं। मूल रूप से यह दल लोकतानिक है क्योंकि दल के सदस्यों को नेताओं की आलोचना करने तथा उह दल से पूपक करने के अधिकार प्राप्त हैं।

फास की राजनीति में इस दल का विवीय प्रमाव रहा है। लियोन ब्लूम और राष्ट्रपति विसेट ओरियल समाजवादी थे। 1946 ई के पश्चात इस दल का प्रमाय कम होने लगा है। 1958 ई में फेंच समा में इसके केवल 40 सदस्य रह गय थे।

उप समाजवादी बल (The Radical Socialist Party)—उप समाजवादी दल की स्थापना 1901 ई में हुई थी। तृतीय गणत न-काल इस दल का सबस उज्जवल समय था। इसके अधिकाश सदस्य मध्यमवर्षीय व्यक्ति थे। दितीय विदवपुद्ध-काल मं इस दल ने जमनी का पक्षपोषण किया था। फलत यह दस म लोकप्रिय नहीं रहा और चतुव गणराज्य काल म इसकी शक्ति क्षोण हो गयी। लिन 1951 ई में इसे असेम्बली मं 75 स्थान प्राप्त हुए थे और इस दल के इस काल में 8 प्रधान-मंगी वने।

कायकम की हृटिट से प्रारम्म म यह दल सिवधान के सरोधन, एनसदनीय व्यवस्था तथा रेल, सानें और फान्स नी बनो के राष्ट्रीयकरण का परापाती था, सेनिन

1050 | आधुनिक शासनतात्र

धीरे-धीरे इसके समधको थे ग्रामीणो एव कृपको की सख्या बढने लगी। इसका आर्थिक कार्येकम उदारवादी हैं। यह वामपथी दल नही है। अधिक से अधिक इसे दक्षिण-वामपपी कह सकते हैं। देलीय सगठन का स्वरूप विकेष्टित है। स्थानीय दलीय निकायों को स्वर्त नता प्राप्त है। दलीय सगठमें और दक्षिणपथियों में विमानित है। वामपियों को नता नती का सा से वे। दक्षिणपथियों को समधक और नियोजन के विरोधी थे।

लोकप्रिय गणतम्त्रीय आ बोलन—दितीय विश्व युद्ध के पश्चात फेच राजनीतिक रगमच पर इस रल (M R P) का उदय हुआ या और यह फास के दो प्रमुख राजनीतिक रको में से ची एक या। एम आर पी लोकप्रिय लोकत त्रीय दल (Popular Democratic Party) का उत्तराधिकारी है। इस दल के साथ फेच राजनीति से प्रथम बार एक बडे एव सुषावित दल का उदय हुआ या जो विमित वहे दलों से सतुतन कायम रखते तथा कैंचीतिक चच की लोकत त्रीय एव अद-समाजनायों नीतियों के समज्य में सफल हुआ या। इस दल के नेता जॉज विदोलत, एड्री कोलिन, जूमान, रोबट चूमा, सभी फासीचाद के विद्ध सथय करने वाले लोकप्रिय नेता ये एव उन्हें जनरल डिमान का वासीवीद प्रस्त या। 1945 ई के निर्वाचन म इस दल को 151, 1946 ई में 166, 1951 ई म 85 एव 1957 ई में 72 और 1958 ई के निर्वाचनों में केवल 59 स्थान प्रप्त हुए थे। यह दल चीरे धीरे अपना प्रमाव लोता चला गया। इस दल में कथोतिका का बहुमत है तथा समाजवादी इस दल को तथी हमें हम्बट से देखते हैं।

यह कोई धार्मिक दल नहीं है पर जु फिर भी ईसाई आदबों एवं सिद्धा तो से प्रमाबित है। यह दल वम सपर्य ना विरोधी है तथा कमवारियों एवं मालिकों के सम्बंधों को 'यायपुषक सुलमांने का समयक है। वे यूओवाद का अर कराला पूँकी बाद का समाधान नहीं मानते। वे समाज म समठन एवं सस्थाओं में परिवतन के साद का समाधान नहीं मानते। वे समाज म समठन एवं सस्थाओं में परिवतन के साय साथ वैयक्तिक तैतिकता के युधार के भी पक्षपाती है। दल का आयुनिक उदारवाद के कुछ सिद्धा तो म विश्वास है। वैयक्तिक स्वत मता एवं लोकता व इसके मूल माम है। सामाजिक एवं लाधिक विपयों में यह उपवादियों की अपेक्षा वामपर्य की और अधिक मूला हुं वा है। इसका कायकम समाजवादिया की अपेक्षा वामपर्य की और अधिक मूल हुं है। इस उद्धीयन रण एवं सामाजिक सुरक्षा को नीति का समयक है। विदेश नीति के क्षेत्र में दल पूरीपीय एकीकरण एवं विवक्तित क्षेत्रों की सहायता का समयक है। वलजीरिया के प्रश्न पर यह दल दियास की नीति के सहायता का समयक है। वलजीरिया के प्रश्न पर यह दल दियास की नीति के सहायता का सम्बाह दल पूजीवाद एवं स्वाधिकारवादी (totalitarian) विचार को अस्थीकार करता है एवं शांतिपूण चोकतीतिक क्षेत्रारा की नीति व आस्था स्वाह है। काटर एवं हैन के बजुतार यह दल चतुष गणराज्य का मुज्य आधार पा। स्वत मता कर परचात प्रत्येक कप मित्रमण्डल म यह दल धारिम खुट हो और विदेश-

म जालय पर इस दल का एकाधिकार था। लियोन ब्लूम के समाजवादी मिजमण्डलों को छोडकर रोबट शुमा एव बिदोल्त के रूप भे यह बनेक फेच मिजमण्डला को प्रधानमात्री प्रदान करता रहा है। बिदोल्त का तो यहा तक विश्वास था कि मिल्प्य म यह दल बहुमत की चुरी प्रमाणित होगा।³

विशाणपथी या अनुदार दल-दक्षिणपथी दला म सबसे महत्वपूण दल French People's Rally (R P F) है। इसे फेंच मापा से 'Rassemblement die Peuple Français' कहते हैं। जनरल डिगाल इसके सस्थापक थे। डिगाल चतुथ गणत त्रीय सविधान से अत्यधिक असातुष्ट थे अत उहीने अप्रैल 1947 ई म इस वल की स्थापना की थी। फ्रेंच राजनीति में डिगाल का प्रादर्भाव 1940 ई म हआ था। फास के जमनी द्वारा पराजित होने पर उन्होने यह घोषणा की थी कि 'फास एक लडाई में हारा है, युद्ध म पराजित नहीं हुआ है। 1947 ई तक इस दल की सदस्य-सख्या करीव 10 लाख थी। 1947 ई के स्थानीय शासन के निर्वाचनों मे दल की कुल मतदाताओं के चालीस प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे। 1948 ई के गणत प्राप्त पद के निर्वाचनों में दल को असाधारण सफलता प्राप्त हुई थी। 1951 ई से दल म मतभेद बढने लगे। डिगाल दल के शासन म शामिल होने के समयक नहीं थे। उनकी इण्छा के विपरीत कुछ सदस्य इस नीति के विरोधी थे। 1952 ई म कुछ सदस्य दल से प्रथम हो गये और उन्होंने 'सामाजिक एव गणत त्रीय सघ' के नाम से एक नवीन दल का गठन किया। 1953 ई के स्थानीय शासन के रिवर्षिकों में दल को बडी असफलता का सामना करना पडा था। 1956 ई तक दल किसी प्रकार चलता रहा। डिगाल दल से पृथक हा गये थे । 1956 ई मे दल ने सामाजिक गणत त्रीय दल के रूप में निर्वाचनों में माग लिया । फार्स में धीरे धीरे डिगालवाद प्रवल होता गया था और 1956 ई तक डिगाल फेच राजनीति पर पूरी तरह छा चुके थे।

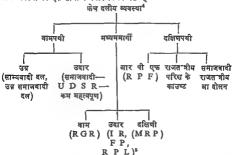
1958 ई के निर्वाचनों के कुछ सप्ताह पूब विगासवाद समयक विभिन्न राज-नीतिक समूद्दी की सम्मिलित करके नवीन यणत श्रीय सम (Union of the New Republic—U N R) नामक दल की स्थापना की गयी। सामाजिक गणत त्रीय दल हसका ही एक अग वन गया था।

डिवाल के दक्षिणपूर्या दल आर पी एफ (RPF) म फासीवादी विचार-धारा के कुछ तत्व थे। इसने एक साथ राष्ट्रीय उत्थान एव सामाजिक कान्ति, स्थप के

उ पहुले दक्षिणपथी दला से तात्पय राजत त्रीय दला से या । आज राजत त्रीय ध्यवस्था का कोई समयन नहीं करता है । अत सर्वाधिकारी निरमुश्तत त्रीय ध्यवस्था में विश्वास करने वाले दल दक्षिणपथी दल नहलात हैं। एस अनुवारवारी दलों की एक विशेषता यह होती है कि वे परम्परा क समयक होते हैं। उस दिक्षणपथी दला म फाबीवादी या फासीवाद-समयक दला को धार्मिक , जाता है।

दलीय भगडों को समाप्त करके सवल शासन की स्थापना और दवाव समूहो एव वर्गीय हिंतों की तुलना म राज्यसत्ता को महत्व देने पर बल दिया था। बार पी एफ मे यह विचार मा य है कि नेता सदैव ठीक होता है एव दलीय नेताओं को समाज के प्रवाध-कीय या कुसीन वम से चुना जाना चाहिए। साथ ही साथ दल समाज के निधन वम के या युना ना भी पक्षपाती है। समीक्षा

विगत 30 वर्षों में फ्रेंच राजनीतिक दलो के स्वरूप में कोई आधारभूत परिवतन नहीं हुआ है। बहुदलीय पद्धति फ्रेंच राजनीति की मुख्य विद्येपता है। प्रधान रूप से फ्रेंच दलों को तीन—वामपंषी, दक्षिणपंषी, एव मध्यममार्थी—वर्षों में विभाजित किया जाता है। इन दलों में भी उग्र एव उदार तथा मध्यवर्ती दल हैं। इस आधार पर फ्रेंच दलीय व्यवस्था का एक सामाय वर्गोंकरण निम्नत है



सभी फ़ेंच दत्ता में आ तिरिक विरोध एवं गुटव दी ब्याप्त है। दत्तीय बहुलता एवं गुटव दी के कारण ही चतुर्थ गणराज्य का अन्त हुआ था। अधिकाश दल सुसग ठित नहीं हैं। दत्तों के संगठनात्मक एवं संसदीय पत्ती में कोई सावयंती एकता नहीं गांधी जाती हैं, फलस्वरूप दत्तीय व्यवस्था का आधार ही घरावायी हो जाता है। विधायका को स्थानीय शासन में बयं पद्मों को ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त है, अत विधायकों की हण्टि से राष्ट्रीय एवं व्यापक संगस्याएँ गोंध हो जाती हैं तथा

⁴ केवल मूख्य मुख्य दलो का ही इस वर्गीकरण मे उल्लेख किया गया है।

⁵ Independent Republicans (I R) The Farmers Party (F P) The Republican Party of Liberty (R P L)

स्वानीय समस्याओं का उनके द्वारा नास्य दिया थाने नवडा है। द्विरतीय व्यवस्था एवं मुन्तप्र दतीय बारकन के बणक में दिशानकपन ने व्यक्तित स्वत्यों हर मान्य बढ़ जाता है। ब्रिटेन के अनुवार वन एक बन वह में मूल विद्यान्ती पर मईस्त है। देवा —सन्देशन बारम्या एव विरोधनीति । सन्तर्मे एक हुन्नमारि है। प्रत्यास्य वसरिक्षी सहायता, नाटो को स्टब्स्टा एवं बम्बन्धन्यों करने की तकर पत्ती में तब नहसेद रातप्र हो पर में । बहरानेय ब्यान्या के राम्यत्म देव रादनीति में रहार-हरूही हा महत्व बढ बया है बौर वे मिनेय प्रमानी है हमा देव की राजनीति न मान्यहर्ष मृतिका निमात हैं। बतुम रमक्तर में बहुदरीय व्यवस्था के कारम अस्मिर एवं अस्मकातिक कमबार मत्रिमन्द्रमों का नियाय दूवा या और मौक्रयाही उन पर हावी एडडी थी। साहत एवं बनुपासन डोला हान के कारण रत के सरूप बनवाने उप से बाबरण एवं काल करते थे । जनक व्यवसा पर अपने एतं के माँत्रयों को पत देन के सम्बन्ध म निर्देश दन के परवात भी दन ने दनको उप उपधा कर हो और बाद में उनका साथ नहीं दिया। बन्त में देव रावनीतिक क्षितिब पर प्रयूप पराज्य के रूप में हिरासबाट का अवतरित होना क्रिडीय दिरमण्योत्तरकालीन कास को सर्वाधिक महन्य-पण घटना है। पत्रम बनद ब-हान में बनीय व्यवस्था ने कोई विशेष स्थार नहीं हैशा है. जह इसीय व्यवस्था का दाय एवं उनकी कनवीरी केंच रावनीरिक प्रयानी ने अभिन्यक होती रहती है।

भारतीय दलीय व्यवस्था

मारत न बनिरहा व हैट हिंदन की तरह केवत दो दना ही हो प्रधानता नहीं है, अनेक अधित नारतीय और अंत्रीय या प्रात्यीय दन तकिय हैं। उदाहरण के तिए, अविका मारतीय कर पर कारते (धारकीय), केवित धपन्न, वनतक, स्वताय पर, अमाजवादी दत, नारतीय धान्यवादी दत धान्यवादी दिन स्वतायों उदा द प्रपानी लोकदन प्रमुख हैं। प्रात्योग दता ने प्रमुख (यिनतवादु) बकाती दता (प्रवाद), तक्तत कार्येद और बारतीय क्वांति दता वादायों कार्येद के प्रार्थीय कीर कार्येद केवित वादायों कार्येद केवित हों से ही प्रवादी केवित वादायों कार्येद केवित वादायों केवित वादायों केवित वादायों केवित वाद्योग केवित वाद्योग

भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषनाएँ मृत्य विशेषवाएँ निम्नवत् हैं

¹ बहदलीय पद्धति—स्वतंत्रता के पूर्व एव बाद में देश की ख

अनेक दलो के सिश्रम रहने के कारण बहुदलीय पद्धित का विकास हुआ है। इसके कई कारण है, यथा—(1) देश की विशालता एव भाषा, घम एव क्षेत्र सम्बन्धी विभिन्नताएँ, (11) वैचारिक विभेद, (11) स्वत त्रता के पूव विभिन्न सम्प्रदायों म पारस्परिक अविद्यास एव सर्देह, तथा [17] पृथक निर्वाचन की पद्धित। स्वतन्त्रता के पूव अखिल सारतीय स्वर पर कांग्रेस, मुसलिम लीग, हिंदू महासभा और उदारवादी प्रमुख दल ये। भातीय दली पे पवाब का यूनियनिस्ट दल, मद्रास की जिस्टस पार्टी, खूदाई खिदमतगार, अकाली दल, घगाल का क्रुपक प्रजा दल एव बम्बई का लोक तानिक स्वराज्य दल प्रमुख थे। स्वतन्त्रता के बाद अखिल भारतीय और प्रातीय दलों में सीतता छे वृद्धि हुई।

मधीप बहुदलीय पद्धति का मारत में विकास हुआ है, लेकिन अखिल मारतीय स्तर पर कियेम देश का सबसे शक्तिशाली दल है। विगत 28 वर्षों से देश की राजनीति पर काग्रेस का एकछन आधिपत्य है। चतुष निर्वाचन के परकात मधीप कुछ राज्यों में गैर काग्रेसी मिनमण्डलों का निर्माण हुआ था लेकिन के द्र में काँग्रेस की ही सत्ता रही थी। अत भारतीय दलीय पद्धति को एकक प्रवत्त लेकीय चति कहते हैं। यह न केवल के द्र के सम्बाध में अधित तिम्हता है। सहार केवल के द्र के सम्बाध में अधित तिम्हता है।

- 2 दलीय मेतृत्व की प्रधानता—मारतीय दला में नेता का प्रमुख स्थान होता है। स्वत तता के पूज भी यही स्थिति थी। 1947 ई तक कार्येस दल म महास्यां गांधी की स्थिति प्रमुख थी, चाहे वे दल के सदस्य रहे या नहीं। स्वत तता के बाद जवाहरताल नेहरू और वतमान में इदिया गांधी का दलीय नेतृत्व में प्रधान स्थान है। अन्य दला की मी स्थिति यही थी। उदाहरणाय, स्वत म्वता के पूर्व मुहस्मक्षती जिता मुससिम लीग के सर्वेसवाँ थे। स्वत म्व मारत मे जनस्य मे स्वर्गीय एशामाप्रसाद मुकर्जी और उनके पश्चात स्वर्गीय दीनदवाल उपाध्याय की स्थिति के द्वीय भी। स्वत म पार्टी में चन्नवर्गी राज्याचालाचारी, मारतीय कात्ति दल में चौ चरणींवह जीर द्वमुक म स्वर्गीय अग्रादुराई (वतमान म श्री करणानिथि) की स्थिति के द्वीय है। ससीप म, समुण दल दलीय नेतृत्व के वारों और वस्कर मारता है।
- 3 सुबद्ध एव सशक्त विरोधो दल का अभाव—बहुदलीय पद्धति एव काँग्रेस के प्रवल बहुमत के कारण स्वतक एव सुसगठित विरोधो दल का निर्माण नहीं हुवा है। फतस्वरूप व्यवहार में देश में एकदतीय—काँग्रेस का—धासन सा स्थापित ही गया है।
- 4 आत्तरिक पुटबंबी—श्राय प्रत्येक मारतीय दल म मतभेद और गुटबंदी विद्यमान है। उदाहरण के लिए, इसी मतभेद क फलस्वरूप कथित का विषटन हुआ है। जनसव स बलराज मधीन पृथक हो गयं। साम्यवादी दल मी मारतीय साम्यवादी और साम्यवादी मानसवादी दल मे विषटित हो गया है। हमुक

मी दो दलो में विमाणित हो गया था और अना द्रमुक नामक नवीउ दल का निर्माण हुआ है। स्वतान पार्टी से गुजरात में सी सी देताई पृषक हो गये थे। इस गुटदादी के प्रमुख कारण हैं व्यक्तिगत महत्वाकाक्षा, प्रतिस्पर्धा, कैचारिक मत्तमेद और सत्ता-प्राप्ति की होड़। यही दल-बदल के कारण हैं। चतुय निर्वाचन के पश्चात देश में 'आया राम गया राम' का ऐसा थुग आ गया था कि अनेक राज्यों में राजनीतिक अस्पिरता एवं अप्टानचार ब्याप्त हो गया था।

5 अलोकत जीव बलीय सगठन—के सवानम का मत है कि दलो का सग ठन और कार्य पद्धति देश की वर्तमान सघीय समदीय व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। पुराने दला ने इसके अनुरूप सगठन और काय-गद्धति में कोई परिवतन नहीं किया है।

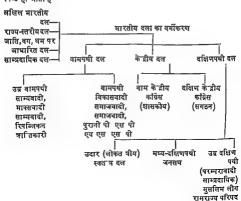
कुछ नवीन दलो--जनसघ एव स्वतान दल--ने भी अय दलो की माति ही अपन दलीय सगठन स्थापित किय हैं। यह सभी दल 'लोकता त्रिक के द्रीकरण' की साम्यवादी भारणा पर आघारित है जहा सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की तरफ होता है. यद्यपि इ ह लोकप्रिय आधार का रूप प्रदार किया गया है। द्रमुक (तमिलनाडू) जैसे दल इसका अपवाद है। 'इन तथाकथित राष्ट्रीय राजनीतिक दला का प्रधान दोप यह है कि यह न तो लोकत नीय हैं, न सघीय, न आज्ञाकारी (loyal) और न अनुशासित। शीपस्य दलीय कायपालिका का दल पर अधिनायकत्व होता है और इसे हाईकमाण्ड की सज्ञा दी जाती है।' जिस राज्य मे जो दल सत्ता मे होता है वहाँ मुख्य मन्त्री एव अय मित्रयो को दलीय नेताओ द्वारा ही मनोनीत किया जाता है। दलीय नेतत्व मन्त्रिमण्डल को निस्न एव अधीनस्य अभिकरण मानता है। काग्रेस हाईकमाण्ड द्वारा राज्यों के दलीय सगठनों को मंग करके उनक स्थान पर तदथ समितियाँ नियक्त की जाती हैं। इसके अतिरिक्त दल के सगठनात्मक पक्ष एव ससदीय पक्ष के मध्य सम्बध अस्पष्ट हैं। कही कही तो वे ठीक उल्टेया विपरीत हैं। स्वतानता के पूर्व दला का सगठनारमक पक्ष प्रबल एव शक्तिशाली था। उस समय एसा होना स्वामाविक था। दल उस समय लड़ाकू थे और प्राय सभी दल देश की स्वत त्रता के सम्बाध म एक्मत थे। लेकिन स्वत नता के पश्चात स्थिति बदल गयी है। दला क प्रमुख नता ससद या विधानमण्डलो के सदस्य चुने गये हैं। एसी स्थिति म सगठनात्मक पक्ष की प्रधानता अनुचित है। यह बास्तविकता की उपेक्षा है। सत्य तो यह है कि दल का सगठनात्मक पक्ष यदि ससदीय पक्ष से प्रवल रहता है, वो उसके द्वारा ससदीय कार्यों म अनुचित हस्तक्षेप किये जायेग एव ससदीय नेता समठन या दलीय नताना क निर्देगा का अनुगमन मान करते रहेगे। यह व्यवस्था साम्यवादी दलीय पद्धति का अनुगमन मान होगी ।

⁶ Santhanam, K "Political Parties and Indian Democracy," Indian Parties and Politics, 1972, pp. 1 3

1056 | आधुनिक शासनत न

भारतीय दलो का वर्गीकरण

मारत के विभिन दला का निम्न वर्गीकरण सम्भव है—(1) अखिल भारतीय दल—काग्रेस ग्रासकीय, काग्रेस समठन, जनसम, स्वत य एव साम्यवादी दल, (2) क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय दल—भारतीय वात्ति दल, द्रमुक, विश्वाल हिर्स्याणा पार्टी, केरल काग्रेस, उत्कल कांग्रेस आहि, (3) आतीय, वर्गीय एव धार्मिक दल (मुसलिम लीग, काली दल), (4) साम्प्रदायिक दल (हिंदू महासमा, मुसलिम लीग, राम राज्य परिपद)। इस वर्गीकरण के अतिरिक्त दलो को वामपथी एव दक्षिणपथी वर्गों में मी विभाजित कर सकते है। साम्यवादी एव समाजवादी दल वामपथी हैं तथा स्वत प्र एव जनसम और अन्य सभी साम्प्रदायिक दल दक्षिणपथी दल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ एसे दल हैं जो इन दोनो वर्गों में नहीं आते हैं। इन दलो की नीतियो म दोना प्रकार की नीतियो—दक्षिण एव वामपथी—का समयव मिनता है। यत इन्हें केदीय (Cen terist) दल कह सकते हैं। काग्रेस (शासकीय) एव सगठन कांग्रेस इसी क्षेत्री में हैं। इन तीनो प्रकार के दलो को भी वाम एव दक्षिण क्षेत्रम देश करने से दिखति अधिक स्पष्ट हो जाती है। निम्नाकित रेखाबिन से मारतीय दलो का वर्गीकरण स्पट हो जाता है—



हिन्द्र महासमा

प्रमुख भारतीय दल

अिस्त भारतीय काँग्रेस — यह देश का सबसे पुराना और प्रमावशाली दल है। इसकी स्थापना 1885 ई य हुई थी। भारतीय स्वत नता के सपप मे इस दल ने प्रधान भूमिका निमाई है। प्रारम्भ म किंग्रेस विटिश शासन के अ तगत सुधार की प्रधानी थी। उस समय इसकी नीति ब्रिटिश शासन से प्रशासन म मुधारी की प्रापना कराना था। उपवाद के उदय के साथ इसने स्थापन के आदश को अपनाया। तिलक ने 'स्वत मता हमारा ज मिति अधिकार है' का शब्यान किया। 1920 ई में गाधीजों के नैतस्व के प्रारम्भ के साथ कांग्रेस जन-स्था बन गयी और उसने स्वत न आ दोलत का नेतस्व किया। यह दल राष्ट्रवाद, लोकत न और घम निर्यक्षता का पक्षमाती है। साम्प्रदायिकता का इसने उटकर विरोध किया। 1947 ई तक कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य स्वत नती प्राप्ति और ब्रिटिश साम्प्राज्यवाद से सदसा था। अत होटे छोटे मतिभद सतह पर उमर कर न आ सके। लेकिन स्वत नता के बाद इस स्थिति का कायम रहना असम्प्रव था। फलत समाजवादी कांग्रेस से पृथक हो गये। इसी प्रकार व्यक्तिवादी उतार विचारधारा वाले थी राजगोपालाचारी और के एम मुनी ने स्वत न वल का निर्माण किया।

काँग्रेस म सदैव ही आतिरिक मतभेद रहे हैं और वे समय समय पर उमरते रहे हैं। इस प्रकार का पहला विस्फोट 1907 ई में सूरत काँग्रेस अधिवेशन म हुआ या और उग्रवादी काँग्रेस से प्रथक हो गये थे। इसी प्रकार पट्टामि-समाप-समय काग्रस मे गुटब दी की दूसरी प्रमुख घटना थी। सुमाप और उनके समयक काँग्रेस से पृथक हो गये। तीसरा अतिम विघटन 1969 ई में हुआ और कांग्रेस तथा संगठन कांग्रेस का जाम हुआ । यह केवल व्यक्तित्वो का ही सर्वय न या अपितु एक सैद्धातिक समय या। कांग्रेस के सगठन पक्ष पर एक विशिष्ट विचारधारा के समयको का अधिकार या। इस बग के नेता लोकत प्र एवं नियोजित विकास में विश्वास तो करते थे पर तु उग समाजवादी नहीं थे। उन पर दक्षिणपयी दलों से मिल जाने के आरोप लगाये गये । इसके विपरीत, इदिरा गांधी दूसरे पक्ष का नेतस्व कर रही थी । वे प्रधानमात्री और संसदीय पक्ष की प्रधान थी तथा लोकतात्रिक समाजवाद की स्थापना के प्रति कृत सकल्प थी । इस समय मे इदिरा गांधी विजयी हुई। कांग्रेस दल दो दलो-काग्रेस शासकीय एव सगठन कांग्रेस-म बँट गया। 1971 ई एव 1972 ई के निर्वाचना मे शासकीय काँग्रेस को मारी जन-समयन प्राप्त हुआ । शासकीय काँग्रेस का राष्ट्रवाद, लोकत त्र, धम निरपेक्षता, असाम्प्रदायि-कता एव समाजवाद म हढ विश्वास है। लेकिन वग सघष एव हिंसा म इसका विश्वास नहीं है। दल सामाजिक परिवतन के लिए हिंसात्मक दाति का समयक नही है। स्वत पता के पूव काँग्रेस शातिपूण वर्षात व्यहिसात्मक कार्य-पद्धति मे विश्वास करती धी। वतमान में 'मत द्वारा परिवतन' में दल की आस्था है। यह दल श्रमिका, पददलिती

एव दोपित वग तथा अल्पसस्यको के हितो का समयन करता है। आर्थिक विकास के लिए नियोजन में विक्वास रखते हुए इन मिश्रित अध-व्यवस्था की नीति को मानता है तथा मारी उद्योगा के ओदोगीकरण का पहापाती है। काँग्रेस (दा) ने नरेखों क प्रीवोगस का उम्रतन किया है। विद्यानीति म विक्व-दात्ति एव समुक्त राष्ट्र स्थ तथा गुट-निरोधित का समयक है।

कांग्रेस का सगठन--कांग्रेस का सगठन पिरामिडाकार है। इसके शीप पर कांग्रेस अध्यक्ष होता है। स्वतन्त्रता के पूब इसे राष्ट्रपति कहते थे। कांग्रेस अध्यक्ष के अतिरिक्त के द्वीय सगठन के चार अप अग हैं—कांग्रेस कायकारिणी, अखित भारतीय कांग्रेस समिति, कांग्रेस सम्वदीय बोड एव के द्वीय निर्वाचन मिनित । कांग्रेस अध्यक्ष नवीनत्त्रम रक्षीय निर्वाचन मिनित । कांग्रेस अध्यक्ष नवीनत्त्रम रक्षीय निर्वाच के अनुसार तीन वप के लिए निर्वाचित होता है। कांग्रेस कायकारिणी में कांग्रेस अध्यक्ष एव 20 अय सदस्य होते हैं। अखित मारतीय कांग्रेस समिति दलीय ससद है। सिद्धान्त्रत कांग्रेस कार्यकारिणी इसी के प्रति उत्तरदायी होती है। कायकारिणी में दल के प्रख्य नेता होते हैं, कई सदस्य तो कांग्री लम्बे समय तक इसके सदस्य बने रहे हैं। अपित भारतीय कांग्रेस समिति म तीन प्रकार के सदस्य होते हैं, जिन्न एवं सम्बद्ध सगठनों के प्रतिनिधि ।

के द्वीम ससदीय बोड में काग्रेस अध्यक्ष एवं पांच आय सदस्य होते हैं। इसका काय दल की ससदीय फियाओं का निय त्रण एवं समावय करना तथा उस व्यवस्थित करना है। के द्वीय निर्वाचन समिति निर्वाचन-काल में सिक्य रहती है एवं दलीय

चम्मीदवारो का अन्तिम रूप से चयन करती है।

राज्य-स्तर पर भी दसो का सगठन इसी प्रकार का होता है । सबसे मीचे ग्राम, मुहल्ला, शहर, ताल्लुका एव तहसील-स्तर पर दसीय सगठन होते हैं। इनके क्रमर जिला कांग्रेस समितियाँ होती हैं। यदेश कांग्रेस समिति एव जिला समिति के क्षोच में क्षेत्रीय समितियाँ होती हैं।

कांग्रेस में सत्ता का प्रवाह उत्पर से नीचे की ओर है। सत्ता चोटी के नेताओं के हायों में केंद्रित होती है। सभी निगय शीय स्तर पर किये जाते हैं, छोटे एवं निम्न दत्तीय सगठमा का मत प्राय नहीं तिवा जाता है। सपानम का मत है कि साम्यवादी दत्तीय सगठन एवं कांग्रेस के दत्तीय सगठन में कोई विद्याय जातर नहीं है। एक अत्तर हिंसा का अवस्य है, पर तु यह अंदर विश्वय पहल का है। अत करिय नेतृत्व को जन समयन प्राप्त करने एवं विभिन्न मामलों में जनता की प्रतिक्रिया जानने हेतु अपने दत्त के ग्राम स्तर से जिला-स्तर तक के सगठना का सहयोग एवं विश्वास भीति-निर्माण के पूर्व प्राप्त करना जाहिए। कांग्रस कायपद्धती से सम्बन्धित एक प्रदेश कोर है कि कांग्रस काय-समितियो एवं कांग्रस मंत्रिमण्डतो व्यांत एक के सगठन एवं ससदीय पश्च मंत्रम सम्बन्ध होने चाहिए रेस्त त्रता के पूर्व तो हद अनुसासक की हिए से कांग्रेस संतर का नियंत्र वा साम्राय साम्य साम्य होने वाहिए रेस्त त्रता के पूर्व तो हद अनुसासक की हिए से कांग्रेस तक का नियंत्र वाहिए ने स्तर प्रता के पूर्व तो हद अनुसासक की हिए से कांग्रेस तक का नियंत्र वाहिया था। पर तु सिन्धान के लागू होने पर

ससदीय व्यवस्था की दृष्टि से यह एक महत्वपूज प्रश्न वन यया है। इसी समस्या को लेकर कांग्रेस मे सथय हुए हैं। 1949-50 ई म श्री जे बी कृपलानी कांग्रेस के व्यवस्था से । अपने पद से इन्होंने इस कारण त्यागपत्र दिया या कि वे शासन पर निय-त्रण की दृष्टि से शिक्तिहोन थे। श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर इसी प्रकार को आपका पुन उठ खड़ी हुई। पण्डित नेहरू इस समय प्रधान म त्री भी से नेहरू एव टण्डन से अनेक बातों मे मत्येद थे। नेहरू जी ने टण्डन जी के पदास्व होंगे पर नासिक सम्मेलन मे अपने बातन की नीतियों म दल के विश्वास को प्राप्त करने की मांग रखी। दल ने तुरत हो उनकी नीतियों मे विश्वास प्रकट कर दिया। तेकिन फिर मी टण्डन जी को अपने कायकाल के बीच मे ही पद से हटना पड़ा था। इस समस्या का केवल एक यही समाधान है कि सगठन पत्र को ससदीय पक्ष के मामलों मे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सगठन पत्र को सलीय प्रचार एव निर्वापन तक अपने को सीनित रखना चाहिए।

भारतीय साम्यवादी वल — इसकी स्वापना 1925 ई वे हुई थी। यह मानस-वादी तेतिनवाद के सिद्धातो पर आधारित है। 1926 27 ई के एक्सात दल ने श्रमिको एव क्रयक-आ-दोलनो का सगठन किया था। 1935 ई मे दल में केवल एक हजार सदस्य थे। 1943 ई म यह सक्या बढकर 16 हजार तथा 1947 ई मे 90 हजार हो गयी थी। स्थापना के समय से ही दल को अवध घोषित कर दिया यया या, लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध काल म पश्चिमी राष्ट्रो से सोवियत रूस की मैश्री हो जाने के कारण साम्यवादी दल पर से सभी प्रतिबंध उठा लिये गये थे और दल सासन के युद्ध सम्बंधी कार्यों का समर्थन करने लगा था। दल ने 1942 ई के 'नारत छोडो' आयोजन का समयन नहीं किया। फलस्वरूप जहे कार्यस से निफ्लासित कर दिया गया।

स्वतात्रता के पश्चात साम्यवादी दल म दो गुट बन गय थे। एक गुट तो अग्रेजो द्वारा सत्ता के हस्ता तरण की वास्तविक मानता या और नेहरू सरकार का समर्थेक था। पी सी जोधी इसी मत के थे। लेकिन वी टी रणविवे इसके विरद्ध थे। जनका दल मे बहुमत था। जोशी को दल से निष्कासित कर दिया गया। रणविवे के नेतदब मे वामपथी हिंसास्मक नीति का अनुगमन किया गया। तेलगाना हिंसास्मक किसान छापामार युद्ध संगठित किया गया। फलस दल के अनेक नेताओं को बादी

1951 ई में रुणदिवें को दल के महासचिव पद से हटा दिया गया और एस के डागे उनके स्थान पर महासचिव बनायें गये । उन्होंने हिसात्मक रणनीति की निदा की।

1952 ई के प्रथम निर्वाचन में साम्यवादियों को लोकसभा में 27 स्थान और विभिन्न राज्य विधानमण्डला में 181 स्थान प्राप्त हुए थे। 1956 ई के निर्वाचनो में साम्यवादियों को लोकसभा में 29 स्थान मिले थे। केरल में साम्यवादी सरकार का निर्याण हुआ था। पश्चिमी बंगाल और आंध्र में बह प्रमुख विरोधी दल था।

मारत चीन सीमा विवाद एव भारत पर चीन के आक्रमण के फलस्वरूप दल दो वर्गों में विमाजित हो गया। श्री डागे ने सीमा विवाद म मारत का समधन किया और चीनी साम्यवादी आक्रमण की निदा की। इसके विपरीत, कुछ नेता चीन सम-यक दृष्टिकोण भी रखते थे। अत्तर्राष्ट्रीय जगत मे भी साम्यवादी दो गूटो मे बेंट गये थे--सोवियत समयक और चीन समयक । भारतीय साम्यवादी दल ने सोवियत रूस का साथ दिया । पश्चिमी बताल साम्ब्रवाटी टल ने चीन के साम्यवादी दल का सम-थन किया। फलस्वरूप 1964 में दल विघटित हो गया और ए के गोपालन और नम्बूदरीपाद जैसे उछ वामपथी नेताओं ने नय दल का निर्माण किया । इसे साम्य-वादी मानसवादी दल कहते हैं। दोनो दलो मे अनेक वातो मे मतनय है। उदाहरण के लिए, दोनो ही बैको, विदेशो ब्यापार व एकाधिकारी पूजी के राष्ट्रीयकरण एव साव जिनक क्षेत्र तथा राज्य व्यापार के समयक हैं। दोनों में अनेक प्रश्नो पर मतभेद हैं, यथा-साम्यवादी मानसवादी दल श्रमिको को ही जाति का नेता मानता है, जबकि साम्यवादी दल सामाजिक काति के लिए अय वर्गों के सहयोग की भी आवश्यक मानता है। मानसवादी बतमान शासन को अपदस्य करने के लिए 'जनता के लोक-तारिक मोर्चा' के सगठन के पक्षपाती हैं, जबकि साम्यवादी दल ने इस सम्बन्ध में कोई मत व्यक्त नहीं किया है। मानसवादी दल भारत-चीन सीमा विवाद को शातिपूर्वक निपटाने पर बल देता है. जबकि साम्यवादी दल सीमा-दिवाद के सम्बाध में भारत सरकार का समयन करता है। 1967 68 ई म मानसवादी दल मे मतभेद उत्पन्न हो गये हैं। दल के उपवादी सदस्या ने 'ससदवाद के द्वारा समाजवाद' की स्थापना में स देह व्यक्त किया और उ होने इसके निपरीत कृपक विद्रोह एव सशस्त्र विद्रोहों के सगठन एवं इस सम्बंध म चीनी साम्यवादी दल का अनुगमन करने पर वल दिया है। फलस्वरूप बगाल मे उग्रवादी मानसवादियों ने एक नये दल का गठन किया था। इस दल का नाम भारतीय साम्यवादी (मानसवादी लेनिनवादी) दल है । ये उप्रवादी नक्सलपथी थे। उपपथी माओवादी थे। आ झ के उग्रपथी उपरोक्त दल मे शामिल नहीं हुए । उन्होंने आ ध्र म श्रीकाकुलम् जिले मे चक्तियाली आ दोलन संगठित किया था। केरल मे कोसलाराम ने इसी तरह ना एक नया दल सगठित किया। स्वर्गीय चारु मजमदार मानसवादी-लेनिनवादी दल (ननसलपथी) के अध्यक्ष थे। वे माओ स्ते तग सं प्रमावित थे । मानसवादी-लेनिनवादी दल उग्नपथी है । ससदीय व्यवस्था म उनका विश्वास नहीं है और न मत द्वारा परिवतन म उनकी कोई आस्या है।

अत देग में आज तीन मुख्य साम्यवादी दल हैं साम्यवादी दल, साम्यवादी

(मानसवादी) एव साम्यवादी (मानर्सवादी-लेनिनवादी ननसलपथी)। इनमे प्रयम ससदीय दल हैं। सोवियत एव चीनी साम्यवादी दल की माति मारतीय साम्यवादी द के सगठन लोकतान्त्रिक के द्रीकरण पर आधारित है। दल मे महाम त्री की स्थि के द्रीय है।

भारतीय जनसध-स्वर्गीय डा इयामात्रसाद मुकर्जी ने 1951 ई मे भारते

जनसप की स्थापना की थी। यह दल लोकत न, वैयक्तिक स्वत नता, भूमि सुधा जमीदारी उ मूलन, स्ववेशी एव आत्मिनगरता, विना छत विदेशी सहायता, गोव निपेम, आर्थिक एव प्रतासनिक विके द्रीकरण उद्योगों में निजी स्वामित्व एव उ प्रोत्साहन, असमानताओं के उ मूलन के लिए कराधान, अस्पनक्षों के प्रति लोक स्ववहार, मारत के साथ कस्पीर के पूल विलय, परिपणित जातियों के उत्थान, हिं को राष्ट्रमाण पदपर प्रतिक्तिक करने एव नि शुरूत प्रारिमक शिक्षा, मुहद विदेशनीं राष्ट्रमण्डल में भारत की स्थिति के सम्बाध में पुनविचार का समयक है। अखा मारत एव विमाजन को समाप्त करने की माग दल ने अपने दितीय निर्वाचन के सम्बाध में पी। पाकिस्तान के प्रति दल काहिष्युत्त का प्रयाप पदम में के समान समयक है। इसके अतिरिक्त इस बहार समापत एव समी धर्मों के समान समयक है। इसके अतिरिक्त इस बत ने सामाजिक आर्थिक कायकम में मूल विचार के सिए आयोग की स्थाना विदेशी सहायता व द करने, साम्पत्तिक अधिकार व सुरसा, 14 वय तक के बातकों को नि शुक्त विदात, हिम्रयों को समान अवसर, विदेश सुरसा, 14 वय तक के बातकों को नि शुक्त विदात, हिम्रयों को समान अवसर, विदेश बेकों के राष्ट्रीयकरण, आणुविक अस्तों के हिमाण, छोटे एव मध्यम उद्योगी की प्रीत

हुन का भी समयन किया था।

प्रथम निर्वाचन म जनसब को लोकसभा मे केवल तीन स्यान प्राप्त हुए थे

1957 ई म लोकसभा म 4, 1962 ई मे 14, 1967 ई म 31 स्थान तथा राज्य
विधानमण्डलों मे 176 स्थान प्राप्त हुए थे। चतुष्य निर्वाचन मे भी कुछ राज्या।
जनसय को काफी सफलता प्राप्त हुई थी। जनसय उत्तरी भारत के हिर्दी प्रदेशा।
ही अधिक लोकप्रिय है। लेकिन 1967 ई के पश्चात दल को आध्र एव मसूर राज्य
में भी विधानमण्डलों के निर्वाचनों मे सफलता मिली थी। 1971 ई मे जनसप के
सगठन कांग्रेस, सक्षीण एव स्वत्य वस्त में निर्वाचन सम्बन्धी गठव धन किये थे
सोकसभा में 1971 ई के निर्वाचनों मे जनसथ को धरस्य सस्था केवल 22 एवं राज्य
विधानमण्डलों में 102 रह गयी थी। 1967 ई के निर्वाचना में दिल्ली के केद्र
प्रशासित क्षेत्र में जनसथ सत्तास्त्र हुआ था। उत्तर प्रदेश म चरणिंग्रह मित्रमण्डल में
जनसथ एक सहयोगी के रूप में धार्मित हुआ था।

प्रकट हुए ये । भागक और साधी जनसम स हट गये । मधोक ने भारतीय राष्ट्रीय लागतानिक दल नामक नवीन दल का निर्माण किया था ।

जनसप के अधिकाश सदस्य हिंदू हैं। मुसलमाना की सस्या नगण्य है। कमठ कायनता एव राष्ट्रीय स्वयसेवक सम दल की शक्ति हैं। बारतीय राष्ट्रवाद एव लाकत म इसका विस्वास है। भारतीय राष्ट्रवाद से इसका लामप्रमाद हिंदू राष्ट्रवाद है। यह अधित भारतीय दक्षिणपयी दल है। वों स्थामाप्रसाद मुकर्जी ने इसका राज्दन किया वा कि जनसप साम्प्रदायिक है सिक्त दल की विचारधारा निम्मवही साम्प्रदायिक है। इनके अधिकाश धरस्य हिंदू सम्यता और संस्कृति से प्रेरणा प्राय्त करते हैं।

स्वतन्त्र दल-1959 ई (अगस्त) म श्री चत्रवर्ती राजगोपालाचारी के प्रयत्ना म इम दल का जम हुआ था। प्रो एन जी रुगा, थी मीनू मसानी, श्री कहैयाताल मणिरलाल मुशी इसके सस्यापन सदस्या मथे। यह दल राज्यवाद एव निरन्तर यद्धं हुए कर-मार का विरोधी है। यह वयक्तिक स्वतात्रता एव लोकतात्र, प्रशासनिक इमानदारी, मावजनिक जीवन म नतिकता तथा वैयक्तिक उद्योग-याथा का समर्थक है। देंग की मुरक्षा क लिए मुद्दद सना की यह आवश्यक मानता है। केंद्रिन नियी-जन का विरोधी है एवं कांग्रेस की समाजवादी नीतिया की अपेक्षा प्रमतिशील उदार-वादी' नीति या ममधक है, सामाजिक याय एव बल्याण या पक्षपाती है एव राजरीय पुँजीबाद तथा सासन द्वारा सोयण का अन्त चाहता है। यह भारत का अनुसार दल है। इगरी आधिक व सामाजिन नीतियाँ प्रतिगामी एवं कायकम रूढ़िवादी है। इस दल म भूतपूर्य नरेशा, सामन्ता, पूंजीपतिया जिनका वि लावनात्र स कोई सम्बाध नहीं है, वा बाहुत्य रहा है। वायस राज्य का इस दल क नता 'परमिट-लाइसे म-काटा' राज्य पहत है। इपि क्षेत्र म यह दल सहकारी कृषि एव पक्वादी का विराधी है। गुट निरुपक्ष निद्यानीति की ठीव भारताचना करते हुए परिचमी गुट म सामिल होने का हिमायती है। स्थतात्र दल की 1962 है के निर्वाचना म साकसमा म 22 स्थान एव राज्य विधानमण्डाना म 166 स्थान तथा 1967 इ. म लास्साना म 44 स्थान एव राज्य विधानमण्डला भ 255 स्थान प्राप्त हुए थ । 1967 ई म स्थलात्र दम सारगंत्रा म तुमरा गुबन बढा दन या । मध्याविष निवायना म स्वत त तत न सम टा कोचन, जननप एवं समाना कं माथ पुनाव पटवं पा क्या पाररपु उसे अन फनता जान हुई थी। 1972 ई व राज्य विधासना व निर्वाचन स्वाम समस्ता का माम स करना पढ़ा है। जहांना म स्वतात्र दल को दि एवं गुफ ता जाप्त होती th far

स्वतान पर के नेपाना में ना महन्द एवं पूट है। 1969 हैं में कीवन दिय दर के मन्द्र मुक्सार के स्वतान पानि महत्त्वमान महत्त्व भी गांधी हमाद र मुक्सात महिर द्राप्त देश महत्त्वर को नदपस्य करने के लिए मानकोय कीवन जो स्वतान्य सर के बंद भर का मुख्यन पिना या। महिन पान नेपानी का यह महिस्स हमाहित नहीं या। श्री देसाई ने इस पर क्लीय नेताओं के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। फलत उन्हें दल स पृपक कर दिया। या। गुजरात के स्वतान दल की शाला ने श्री देसाई का समयन किया और केन्द्रीय निर्देश का अनुषमन नहीं किया। फलस्वरूप गुजरात के स्वतान दल स फूट पड संयी। अनक नेता दल सं उदासीन हो यथे। दल की आत्मा श्री राजानी वाचा यो गुजी का निवन हो चुका है तथा श्री राजा ने दल से पृपक होकर कार्या (सा श्री राजानी अव्या श्री राजानी कार्या श्री स्वतान की सा श्री पील मोदी ने मारतीय लोकदल नामक नवीन दल में स्वतान दल के विलय का समर्थन किया। फलस्वरूप स्वतान दल का सारतीय लोकदल में विलय हो गया है।

समाजवादी दल-मारत में समाजवादी दल की स्थापना स्वत प्रता के प्रव 1933 34 ई मे कांग्रेस के मीतर एक दल के रूप म हुई थी और इसे कांग्रेस समाज-थादी दल के नाम से पुकारा गया था। स्वत नता के पश्चात 1948 ई म यह दल काँग्रेस से प्रथक हो गया । प्रथम निर्वाचन के पश्चात सितम्बर 1952 ई में समाज-वादी दल एव आचाय कृपलानी का किसान मजदूर प्रजा दल परस्पर विलय हो। गर्म थे। इस नवीन दल को प्रजा समाजवादी दल (प्रसोपा) की सजा दी गयी। आचाय कुपलानी इस नवीन दल के अध्यक्ष एव अशोक मेहता महामानी बने थे। लेकिन एक इकाई के रूप मे यह बहुत दिनो तक न चल सका। विलय होने वाले दोनो दला मे कायनम्, पद्धति, आदि का भेद था। यह मतभेद धीरे धीरे उमर कर सामा आने लगे। राममनोहर लोहिया काग्रेस एव साम्यवादी दोना से किसी भी स्थिति म सम्बन्ध स्थापित करने के विरोधी थे। इसके विपरीत कुछ अय नेताओं का मत था कि जिन राज्यों में साम्यवादी एवं साम्प्रदायिक शक्तियाँ अधिक सबल हो उन राज्यों में दल को काग्रेस का समयन करना चाहिए। केरल के पट्टम यानू पिल्ले के शासन काल में हुए गोली काण्ड को लेकर दल मे तीय विवाद उत्पत्र हो गया और 1954 ई म श्री लोहिया दल से प्रयक्त हो गये तथा 1955 ई में 'समाजवादी दल के नाम से नदीन दल का निर्माण किया। उसके पश्चात प्रसीपा एव सोपा पृथक-पृथक रूप में कायम रह। 1971 ई मे दोना दल पुन मित्र गये और भारतीय समाजवादी दल की स्थापना हुई। कई बार दोतो दला के विलय की चर्चा चली थी। यह दोना दलो के हित म





नवीन समाजवादी दल—संसोपा—की स्थापना हुई थी। कुछ समय तक दोना दला में काफी मेल-जोल बढा पर तु 1965 ई में वह पूरी तरह समास्त हो गया और प्रसोपा की पुन स्थापना हुई। श्री हरिविच्णु कामय ने इस वार विद्रोह किया था।

ससोपा एव प्रसोपा को देश के निर्वाचनो मे कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं हुई है। द्वितीय ससदीय निर्वाचनों (1957 ई) में प्रसीपा को 19 एवं समाजवादी दल (लोहिया) को 7 स्थान मिले थे। चतुथ निर्वाचन म प्रसोपा को लोकसमा म 13 एव राज्य विधानमण्डलो म 104 स्थान तथा ससोपा को लोकसभा मे 22 एव राज्य विधानमण्डलो मे 177 स्थान प्राप्त हुए थे। इन चुनावो म ससोपा को अपेक्षा-कृत अधिक सफलता मिली थी। लेकिन अक्टूबर 1967 ई मे राममनोहर लोहिया की मृत्यु के पश्चात दल की प्रतिष्ठा को चोट पहची है। 1971 ई के निर्दाचनों में ससोपा ने दक्षिणपथी दलो-सगठन काग्रेस, स्वतात्र एव जनसघ-से चुनाव सम्बाधी गठब धन किये थे। इस निर्वाचन मे प्रसोपा एव ससोपा का सफाया ही हो गया। ससोपा लोकसमा मे कोई स्थान प्राप्त नहीं कर सका । ससोपा को बिहार में 2 एवं मध्य प्रदेश मे 1 स्थान प्राप्त हुआ था। 93 स्थानो पर ससोपा ने चुनाव लढा था, इनमें 62 स्थानो पर उसकी जमानत जन्त हुई। प्रसोपा को कुल 14,10,598 मत प्राप्त हुए थे। 1967 ई के पहचात प्रसोपा की कोई स्पष्ट नीति नही रही और न उसका नेतत्व ही प्रमादशाली रहा। 1971 ई के निर्वाचन को प्रसोपा ने अकेले ही लडा था। 1971 ई के निर्वाचनों में पराज्य से दोनों दला में नराश्य उत्पन्त हो गया। फलत दोनो दला के विलयन का माग प्रशस्त हो गया। जॉज फर्ने बीज ने प्रसोपा एवं ससोपा के विलय से अथक योग दिया था।

प्रसीषा (प्रजा सोशलिस्ट पार्टी) का कायकम निम्नत था

भूमि सुवारो का प्रमावपूण निया वयन, कृषि-उत्पाद का उचित मूल्य निर्धारण, भ्रष्टाचार-उमूलन, प्रतिनिधियों के प्रत्यावतन की व्यवस्था, के द्र राज्य विवादों के तिवारणार्थ आयोग की स्थापना, सहतीय सर्वोच्यता को सा यदा, शहरी सम्पत्ति का परिसीमन, उचित मूल्या की टुकानों की व्यवस्था, भूततम वेतन, सतदार्ग की आयु 18 वप किया जाना, वेदोजवापी मता, वृद्धावस्था पे चल, गुट निरपेसता एव उसका सही क्रिया व्यवन, चीन से उस समय तक सीमा विवाद के सम्ब प कोई समभीता नही निया जाना चाहिए जब तक कि वह आक्रमण द्वारा हस्त्यत की गयी भूमि को खाली नहीं करता, जरव एव इच्चाइस दोनो देशों से मश्रीपूण सम्ब पो की स्थापना तथा समुक्त कराव्य समम तथा विवाद के सम्ब प्रकृत राज्य विवाद के समय सामा किक, राजनीतिक एव आधिक स्रोपण सुक्त कराहीन एव जाविविहोन समाज की स्थापना है। ससीपा एव प्रसोपा दोना ही सोवाज त्रक या विकासवारी समाजवाद म

आस्या रसते थे । ये दोनो दल साम्यवादी एव वामवर्गी हैं । ससोपा अधिक उग्रपथी दल था। परन्तु दोनो दला म सद्धातिक एव कायतम सम्बाधी गम्भीर मतभेद है।

ससीया (सयुक्त सोशलिस्ट पार्टी) का मुख्य कायत्रम निम्नाकित था

ससोपा परम्परागत यूरोपीय समाजवाद से भिन समाजवादी व्यवस्था की स्यापना के लिए प्रयत्नशील या । युरोपीय समाजवाद का विकास क्रमिक सबैधानिक एव वितरणात्मक ढग से हुआ है। पर तु ससीपा के अनुसार मारत म समाजवाद का विकास तीप्रगामी और आवश्यकता पढने पर असवैधानिक ढग से भी हो सकता है। ससोपा के अनुसार उत्पादन पर वल दिया जाना चाहिए। दल को स्वत लोकत त्र के विकास म कोई आस्या नहीं थीं तथा समाज में गम्भीर एवं उग्र परिवतन का वह पक्ष-पाती था । ससोपा उग्र का तिकारी सथप, सुनिश्चित समाजवादी कायकम, उग्र देशमक्ति एव विकेदित लोकतात्र का समयक या । जनचेतना को जागृति करने के लिए अहिसा-रमक कायपद्धति एव असहयोग मे दल की पूण आस्या थी । ससोपा का दलीय काय-कम उप्र था। उदाहरण के लिए, दल नवीन सर्विधान के निर्माण, निर्वाचित काय-पालक अधिकारी, राज्यपाल एव जिलाबीश के पदी की समाप्ति, अग्रेजी के आधि-परय के अत, धम निरपेक्षता एव असाम्प्रदायिकता का समयक था। इसके अतिरिक्त हरिजना के उत्थान के लिए विशेष व्यवस्था, मुख्य उद्योगो एवं विदेशी पूजी का समाजी करण, ब्यापक सप्तवर्षीय सिचाई योजना, बेरोजगारी उम्लन के लिए बेरोजगार निधि की स्थापना, गुट निरपेक्षता के रचनात्मक क्रिया वयन, तिब्बत को स्वाधीन कराने आदि नीतियो का पक्षपाती था। ससोपा कांग्रेस शासन को देश की सबसे बडी बराई मानता था और काग्रेस से सबप को दल प्राथमिकता प्रदान करता था। -समाजवादियो एव प्रतिक्रियावादिया का मी ससोपा घोर विरोधी था। नेहरू एव महरूवाद के विरुद्ध भावाज सवप्रथम डॉ लोहिया न ही उठाई थी।

ससोपा एव प्रसोपा का विलय हो गया है तथा एक समाजवदी दल का निर्माण भी हुना है। लेकिन प्रश्न है कि क्या वास्तव मे दोना दला का विलय स्थायी सिद्ध होगा ? क्या दोनो दलो ने अपना अस्तित्व पुणरूपेण त्याम दिया है ? इसका कोई निश्चित उत्तर एव पर्याप्त प्रमाण नही ह । अपितु ठीक विपरीत साक्ष्य अवश्य उप-लब्ध होने लगे हैं और दल म फूट की बीमारी पुन उमर रही है।

समीक्षा-मारत मे बहदलीय पद्धति है। चतुर्य निर्वाचन एव विघटन के फल-स्वरूप कांग्रेस की जो क्षति हुई थी वह विगत वर्षों में पूण हो चुकी है। काग्रेस (शास-कीय) की स्थिति पुन हढ हा गयी है। अत व्यवहार म विभिन्न विरोधी दला का प्रमाव नगण्य ही है । देश में काँग्रेस का एकमात्र प्रवल बहुमत है । तमिलनाडु राज्य इसका अपवाद है। द्रमुक को छोडकर शेष सभी क्षेत्रीय दलो की स्थित नमजोर है।

Hartmann, H The Socialist Parties of India J C P S Vol V, No 4, Oct Dec 1971 p 648

सभी क्षेत्रीय दलो को अपनी स्थिति का ज्ञान है। कुछ अखिल मारतीय दला की स्थिति भी कमजोर है। ऐसे सात दलों के विलय से 'मारतीय लोकदल' नामक नये दल का उदय 29 अगस्त, 1974 को हुआ है। चौधरी चरणसिंह उसके अध्यक्ष चुने गये हैं। नवीन दल को राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का विकल्प बनाने का प्रयस्त है। इसमे विलय होने वाले सात दल हैं स्वत त्र दल, मारतीय त्राति दल, उत्कल काँग्रेस, ससोपा, लोकता निक दल, किसान मजदूर दल, पजाव खेतीवाडी जमीदार सप। खेति-हर मजदूर सघ भी इसमे शामिल होने वाला था। प्रेक्षको क अनुसार यह दल मीशीघ शामिल हो जायेगा। मारतीय लोकदल देश की राजनीति को गाधीवादी दिशा दना चाहता है और इसने नेहरूवादी नीतियो म सशोधन का निश्चय किया है, कृषि को प्राथमिकता दी गयी है तथा लघु एव कुटीर उद्योगी की द्वितीय एव भारी उद्योगों को तृतीय स्थान दिया गया है। दल ने लक्ष्या के अनुरूप साधन की पवितता पर बल दिया है। यह दल न तो नियानण विहीन शोषण युक्त वैयक्तिक स्वतात्रता का समयक है और न राज्य को इतनी व्यापक शक्तियाँ देन का इच्छुक है जो वैयक्तिक पहल एव आर्थिक स्वतः नता पर अनुचित प्रतिबाध बन सकती हो । राष्ट्रीय स्तर पर काग्रेस दल के विकल्प के रूप मे भविष्य मे इस दल की सफलता पूण सदिग्घ है। दल मे बलराज मधोक, पोलु मोदी, बीजु पटनायक एव राजनारायण जैसे विभिन्न राजनीतिक विचारों के व्यक्ति हैं। अत इसकी सफलता की मुख्य शत यह है कि दल में विलय होने वाले सभी दल किस सीमा तक सब स्वीकृत दलीय कायकम पर निणय कर पाते हैं।

पाकिस्तान की दलीय व्यवस्था

पाकिस्तान में वहुदलीय पदित का विकास हुआ है। पाकिस्तान के जाम क समय केवल वो दल थे—मुसलिम लीग और पाकिस्तान राप्ट्रीय कांग्रेस। मुसलिम लीग का पाकिस्तान के प्रारम्भिक वर्षों में देश की राजनीति पर एकाधिकार था। पाकि स्तान राप्ट्रीय कांग्रेस अस्पस्क दल था और उसके अपर अनेक प्रतिवाध थे। यह पूर्वी पाकिस्तान में अधिक सन्त्रिय था।

मुसलिम लीग

यह दल 1946 56 ई तक मतास्ख रहा। इसकी स्यापना अविमाजित भारत में 1906 ई में हुई थी। पाक के सस्यापक गुहम्मद असी जिना के नेतत्व में इस दल न द्विराष्ट्रवाद के सिद्धान्त का अनुगमन करते हुए पाकिस्तान के निर्माण में उग्र एवं आकामक भूमिका निमाई थी। प्रारम्भ में दल का देश पर एकाधिकार था किन्तु आ तरिक मतमेदा ने दस की श्राक्त को क्षीण कर दिया। पूर्वी और पिक्नी पाकिस्तान मं भाषा के प्रक्ष्म पर गतिरोध उत्पन हो यथ तथा अनेक अय दसो का उदय हजा।

मुसलिम लीग का कोई निश्चित कायक्षम नही था, न कोई निश्चित आर्थिक नीति ही यी। लियाकतक्षती की हत्या के पश्चात लीग में गुटबन्दी बढ गयी। नाजि

मुद्दीन के सत्तारूढ होने के पश्चात पाक राजनीति में प्रातीयता पूरी तरह उमर कर सामने आयी । मुसलिम लीग ने अपने को सत्ता म बनाय रखने के लिए इस्लाम और पाकिस्तान की रक्षा के नारे का सहारा लिया था। 1954 ई के निर्वाचना म लीग का नारा था कि मुसलिम लीग के विरद्ध मत पाकिस्तान के विरुद्ध मत है। इस दल ने सर्देव पाक जनता को यह समफाने की काशिश की कि लीय को अनादि काल तक दासन करने का अधिकार है। यह भ्रम था। 1954 ई के निवाचना म हव, सुहरा वर्दी और मौलाना मापानी के नेतृत्व म संगठित संयुक्त मोर्चा ने पूर्वी पाक म सफलता प्राप्त की । पश्चिमी पाविस्तान मे रिपब्लिकन पार्टी वी स्वापना हुई और मुहम्मद अली के त्यागपत के साथ 1956 ई मे लीग का शासन समाप्त हो गया। मुसलिम लीग के पता का मुख्य कारण पूर्वी पाकिस्तान की जनता म ब्याप्त तीय अस ताप की उपेक्षा करना था। पूर्वी पाक की जनता उद्ग को राष्ट्रीय मापा स्वीकार करने के लिए तयार नहीं थी। लीग का संगठन भी दीपपूर्ण था। एक व्यक्ति--मुख्य नेता-- के चारो ओर वह केद्रित या और एक बार उस नता के हटने में बाद दलीय एकता को कायम रखना कठिन हो जाता था। दल पर वहे-वहे जमीदारा एव पत्री-पतियो ना आधिपत्य था। बासन का दल से एकाकार हा गया था। दलीय नताओ मे नेत्त्व का अभाव था।

पाकिस्तान म सैनिक शासन की स्थापना के पश्चात राजनीतिक दला पर प्रति-व भ लगा दिये गये थे। 1962 ई के शविधान क अपीत समस्तित नमी ध्यसस्यापिता द्वारा लोकत भीकरण को मांग की गयी, फलस्व्य राजनीतिक दलीय अपिनियम पारित किया गया और राजनीतिक दलों के निर्माण और निर्वाचना स आग लेन की अनुमति दी गयी। सितम्बर 1962 ई में परम्परागत मुस्तिम तीय की पुन स्थापना की गया। यह दल पाक मुस्तिम लीग के नाम स विस्थात हुआ। 1963 ई म राष्ट्रपति अप्य मी इसमें शामिल हो गय। 1965 ई क राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय सभी विरोधी दला ने मिलकर समुक्त विरोधी दल वा निर्माण विषय विसमें अगामी लोग, राष्ट्राय अवामी लीग, जामयत ए इस्लामी, निजाम ए इस्लामी तथा काउन्सिल मुस्तिम भीग शामिल थी।

अवामी लीग

इस दल की स्थापना 1949 50 म मुसलिम सीग म असन्तुप्ट और गृथद हुए सरस्या ने की थी। इसन राहीद मुहुरावर्यी इस इस क नता थे। 1953 ई. म. गर्टिय सपुक्त भीचें म यह इस मुद्धा हिस्सेदार था। लेनिन यह गर्ट्य पन अपिन दिना तक न चल सका। मुहुरावर्दी अपने दल को अपिक तोक्तानिक मानत थ। अग्राभी दन ने अपने निर्वाचन पोषणा-यन म निम्म नायकम की पांपणा की थी

'जूट व्यापार का राष्ट्रीयकरण, जूट का उचित मूक्य देना, भू राजस्य का उन्मूलन करना, भूमिहीना म भूमि का विवरण, बहुकारी खेवी एव कुटार उद्योग का विकास, पूर्वी वर्गाल को पूण स्वायत्तवा, वगाली भाषा को शाक की एक राज्यभाषा वनाना तथा यायपालिका और कायपालिका का पृथक्ररण ।"

1956 ई म सहरावदीं रिपब्लिकन पार्टी के सहयोग स पाकिस्तान के प्रधान म त्री बने । उन्होने मुसलिम लीग द्वारा समयित परम्परागत पाक विदेश-नीति का अनुगमन किया। इससे दल मे मतभेद हो गया। मौलाना भाषानी दल से पृषक हो गये । 1965 ई मे राप्ट्रपति के निर्वाचन के समय संगठित संयुक्त विरोधी दल मे अवामी लीग भी शामिल थी। अवामी लीग के नेता पूर्वी पाक के सम्बन्ध म स्वायत्तता के पक्षपाती थे। वे एकारमक ज्ञासन के स्थान पर परिसधीय ज्ञासन (Confederal Government) के समयक थे। पूर्वी पाक अवामी लीग ने पूर्वी पाक की स्वायलता के सम्बर्भ मे छ सुत्री कायक्रम की घोषणा की थी। इसका तीव्र विरोध किया गया। लेकिन दिसम्बर 1970 ई के निर्वाचनों में होल मुजीबुरहमान के नेतत्व में पूर्वी पाक अवामी लीग को असाधारण सफलता प्राप्त हुई। स्मरणीय है कि याहिया ला ने निर्वाचन के पुत्र यह आइवासन दिया या कि निर्वाचन की घोषणा के 120 दिन के भीतर जन प्रतिनिधियो से मिलकर नवीन सविधान का निर्माण किया जायेगा। पूर्वी पाक अवामी लीग की सफलता से गतिरोध उत्पन हो गया। मुजीब की अवामी लीग और भुट्टो की पीपुल्स पार्टी तथा याहिया खाँ के मध्य समभौता न हो सका। पूर्वी पाक में दमन चक्र का आरम्भ हुआ। मुजीव को बादी बना लिया गया। पूर्वी पाक की जनता ने 26 मार्च, 1971 को स्वत त्रता की घोषणा की और लम्बे समय के बाद स्वतात्र बगला देश का उदय हथा।

अय दल

रिपिन्तकन यल—इसकी स्थापना डॉ खान साह्व ने 23 माच, 1956 ई
को की पी। दल ने 14 भूत्री निम्न कायक्रम की घोषणा की 'जीवन-स्तर म बद्धि,
कृषि एव उद्योगा का समान विकास, अध्टाचार, बशिक्षा, मिक्सावृत्ति, वेरोजगारी का
उन्ततन एव भूमि-स्पार आदि।"

विष्य कि निर्मा निर्मित का अनुवानन न कर सका । परिस्पितियाँ इसके लिए उत्तरदायी थीं । उदाहरण के लिए, प्रारम्म म दल ने पिष्टिमी पाकिस्तान को एक इकाई बनाये रखने का समयन किया था, लेकिन बाद में उसके विषटन के लिए आरोलन प्रारम्म कर दिया । दल प्रारम्म में द्विराष्ट्रवाद के विष्ट्व था, लेकिन बाद में पृथ्य निर्वाचन का समयन करने लगा था । बाद म पूर्वी पाकिस्तान के सदम में एक वार पुत इस नीति म परिवतन हुआ और दल से सपुत्त निर्वाचन का समयन किया । दल ने आर्थिक सुधारा की योजना प्रसुत्त नहीं की । उसकी विदेश-नीति स्पट नहीं भी । दल म अधिकाश्चाद मुस्तिस सीम के भूतपुत्त सदस्य थे । रिपिलनकन दल देश

म स्थिरता तान मे सफल नहीं हुवा। प्रारम्भ से ही दल मुसलिय लोग के विरुद्ध था। राष्ट्रीय श्रवामी पार्टी—इसकी स्थापना जुलाई 1957 ई म विभिन्न आठ समूही के एकोकरण से हुई थी। बाजाद पाकिस्तान दल, जी एम सैयद, खान अब्दुल गफ्फार खी के समर्थक, पूर्वी पाक का गणत नीय दलऔर मौलाना भाषानी व उनके समयक इस दल म खामिल हुए थे। गर-मुखलमाना को समानता के आधार पर इस दल की सदस्यता प्राप्त थी। यह बाज पाकिस्तान का प्रमुख विरोधी दल है। खान अब्दुल बती खी इसके प्रमुख नेता हैं। इसका यम निरपेक्षता और समाजवादी विचारी में विश्वास है। 1963 ई में इस दल को दवाने का शासन ने मरसक प्रयत्न किया था। इस दल के ब्यूबदाही के विश्वद हढतापूनक मोर्चा लिया और ससदीय द्यासन की स्थापना के लिए मरसक प्रयत्न किया है। दल खामाजिक और आधिक सुधारों की तरफ विश्वप ध्यान नहीं दे खका है।

पीपुल्स पार्टी—श्री मुट्टो ने 30 नवम्बर, 1967 ई को लाहीर म इस दल के निर्माण की घोषणा की थो। दल के तीन आवल हैं—इस्लाम, समाजवाद और लाकत म। वे इस्लाम और समाजवाद म पूण सर्गात देखते हैं। उनका कथन है कि इस्लाम हमारा धर्म है, लोकता व हमारी राजनीतिक पद्धति है और समाजवाद हमारी अपनीति है। इस जनता वो सम्मृत्ता में विस्वास करते हैं। 1970 ई के निर्वाचन में पीपुल्स पार्टी को अवामी लोग के मुकाबले म कम सफलता मिली। वेगाला देश की स्वत मता के परवात पीपुल्स पार्टी का अवामी लोग के मुकाबले म कम सफलता मिली।

इसके अतिरिक्त 1967 ई म बिभिन्न विरोधी दल-समूही ने पाक लोक तान्त्रिक दल की स्थापना की थी। यह दल लोकत त्र एव जनता की सम्प्रमुता में विषवास करता है। जमायत ए इस्लामी और निजाम ए इस्लामी दो प्रमुख धार्मिक दल हैं। वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इस्लाम धम की प्रमुखता म विषयास करते हैं।

समीक्षा—पाकिस्तान में बहुदलीय पद्धित का विकास हुआ है तथा दलों का उरयान एवं पतन बड़ी शीझ गित से हुआ है। मुस्तिल सीग के पठन के परवात देश की राजनीति पर किसी एक दल का नियं नण गहीं रहा है। पाकिस्तान हस्लामी राज्य है अत सभी दलों ने आधुनिक लोकतान एवं समाजवाद के विचारों और धम-त क की मध्यपुरीन विकारधारों के साथ सगति स्थापित करने के असफल प्रयत्न किये हैं। 1936 है ने परवात पाक म निर्वाचना के समय समस्त विरोधी ममुहाद्वारा सगितित होकर अस्पर्भातिक विरोधी विरोधी दल के निर्माण का प्रयत्न किया जाता रहा है। सभी राजनीतिक दलों ने जन-समयन प्राप्त करने ने लिए भारत विरोधी नीति का सहारा लिया है। जकारिया के अनुसार 1956 ई के पूप पाकिस्तान के राजनीतिक दलों ने निम्नवत् थी

(1) किसी राजनीतिक दल का सगठन सोकत वात्मक नही या और न जनता

से किसी दल का सीधा सम्पक ही था।

⁸ Zakaria, N Parliamentary Government in Pakistan, pp 187 88

- (2) मुसलिम लीग को छोडकर खेप सभी दल क्षेत्रीय थे । पूर्वी पाक में मुसलिम लीग की लोकप्रिय दल नहीं था ।
- (3) देश म अनेक दल थे अत दो ही दल देश की राजनीति में प्रमुख नहीं थे। ससदीय दलीय पद्धति के लिए यह दलीय व्यवस्था उपयुक्त नहीं थी। दला पर नेताओं का नियायण था और दलों का अनुसासन दीला था।
- (4) दला के सदस्य आये दिन एक दल छोडकर दूसर दल में शामिल होते रहत थे। देश की राजनीति म दल वदल का सन्नामक रोग फैला हुआ था और दला म गठब थन होते रहते थे।

जकारिया का उपयुक्त विश्लेषण 1956 ई के पश्चात भी कुछ परिवतन से लागू होता है। पूर्वी पाक में अवासी दल का जनता से निकट सम्मक था एव उसे जनता का स्थापक समयन प्राप्त था। यह 1970 ई के निर्वाचना से सुस्पट है। पाकिस्तान का राजनीतिक जीवन प्रष्ट था। रिश्वत एव चौरवाजारी का वाजार गम था। अपूब के सत्तास्त्र होने पर उन वातो में कुछ समय के लिए कभी आयी थी पर तु अभूवधाही के रूप में निरकुक्षत न की स्थापना हुई और लोकत न का गला थोट दिया गया। गौकरधाही भी ससदीय सासन के पतन के साथ सिक्ताची होती चली गयी। सशक्त विरोधी दल के अमाव ने पाक्सिस्तान में तानाशाही के लिए माग प्रशस्त कर दिया। मुसलिम लोग ने किसी विरोधी दल को उमरने नहीं दिया था एव उनका निमम दमन किया जात रहा।

जापान मे दलीय पद्धति

जापान में राजनीतिक दलीय व्यवस्था का इतिहास पुराना है। 1890 ई मं प्रतिनिधि सासन की स्थापना के पूज ही जापान में राजनीतिक दलों का विकास प्रारम्भ ही चुका था। उदार दल (Juyulo) प्रथम और प्रयतिवित्त दल (Kaishuto) दितीय दल था। इन दलों ने सर्वधानिक सासन के निर्माण के लिए प्रयत्न निया। पर उर्व दितीय दल था। इन दलों ने सर्वधानिक सासन के निर्माण के लिए प्रयत्न निया। पर उर्व 1884 ई म इत दोनो दलों के निमल के सिर्माण के लिए प्रयत्न निया। पर उर्व 1884 ई म इत दोनो दलों ने निमल सर्वधानिक दल (Constitutional Party) का निर्माण किया। कुछ समय वाद प्रगतिवादी इस दल से पृथक हो गये और एक नवीन दल (True Constitutional Party) का गठन किया। 1918 ई म जापान में प्रयत्न दलीय सासन की स्थापना हुई। इस समय पश्चात 'वोकप्रिय सासन को प्रयत्न के स्थापना हुई। स्मरणीय है कि जापान में प्रयत्न विकर्म के वाद लोकतन्त्र का तीव्र गति से दिकास हुना था। 1925 ई में सावभौभिक वयस्क मताधिकार प्रारम्भ हुना। इसी तमय औद्योगिक विकास के कारण प्रमिक दल्की की स्थापना हुई। समाजवादी विचारपारा के थारा दलो—श्विक इपक दल, जापान स्थापन हुई। समाजवादी विचारपारा के थारा दलो—श्विक इपक दल, जापान स्थापन हुई। इन वामपयी दली में एकता नहीं थी। यही स्थित अनुदार दला नी थी। 1931 ई इन वामपयी दली में एकता नहीं थी। यही स्थित अनुदार दला नी थी। 1931 ई

में जापान में सिनिकवाद का उदय हुआ। युवक सैनिक अधिकारिया ने प्रमुख अधि कारियों की हत्या कर दी और शासा म घूस बैठे। 1940 ई में वामपधी और दक्षिणपथी दल राजनीतिक खितिज से तिराहित हुए। दिसीय विदवयुद्ध के समय जापान में केवल दो—सियुलकाई (Scryulkar) एव मिनसीटो (Minscito)—प्रमुख दल थे।

1945 ई में द्वितीय विस्वयुद्ध क पश्चात यह दल अनुदार दला के रूप म उमर कर भागे। इसके अतिरिक्त साम्यवादी दल एव समाजवादी तानतानिमक दल मा भी उदय हुआ। कुछ छोट दला का भी विकास हुआ या। सेकिन 1953 ई में आपान में दिदलीय पद्धित स्वापित हो गयी थी। हो प्रमुख दल ये हैं (1) उदारवादी लोकतानिक दल (Ziyuminshuto), एव (2) वापान समाववादी दल (Nihon Shakaito)।

(1) उदारवादी सोकतािनक दल—यह जापान का अनुदार दल है। 1955 ई में इसकी स्थापना हुई थी। इसे उद्योगपितया और व्यापारिया ना समधन प्राप्त है।

(2) जापान समाजवादी दल—समाजवादी दल का 1947 ई व निवाच को समाजवादी दल का 1947 ई व निवाच के समाजवादी दल का 1947 ई व निवाच के समाजवादी दल का समाजवादी दल का समाजवादी दल का समाजवादी वा समाजवादी दल का समाजवादी के सहयादी वा समाजवादी के सहयादी के वा समाजवादी दल को स्वाचित हुई । एक तम्म समाजवादी दल को समाजवादी दल को

साम्यवादी वल-जापान का यह प्रमुग दत है। यह बापान स जमरिकी गैनिन बहडों की हटान का पक्षणाती है। 1951 जी चारित-सि य को मंमाप्त करन का सम पन है और साम्यवादी गुट का पढ़ पोषक है। यह बापान न नात्त जोय समुक्त मार्थे का प्रतिनिधित्व करता है। बापान न नाम्यवादिया ना प्रनाच पट रहा है। 1949 है में प्रतिनिधि सदन म इसने 35 सदस्य थ। 1958 म यह सस्या पटनर अवस्य 4 रह गरी है।

जापान की दलीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ निम्नवत्र है

- (1) जापानी दलीय पद्धति पारशास्य सम्मता और आपूनिकता का परिधाय है।
- (2) इनक विकास म भूगाल न महत्वपूर भूमिका निवास है।
- (3) दला के विकास और समटा न पन का अमुल हाय नहीं रहा है।
- (4) 1953 ई में बापान में बहुदत्तीय व्यवस्था प्रवर्गित रहा है।
- (5) जापान के सभी दलाका सर्टन एक्सा है जयांत्र प्रायक दक्ष का निर

1072 | आधुनिक शासनत त्र शालय एव आ तरिक विभाग होता है। लेकिन दला की वित्तीय व्यवस्था और अनु-

शासन एक समान नहीं है। सक्षेप में, सही अथों म जापान में राजनीतिक दला का अभाव रहा है। वहाँ

अधिकतर राजनीतिक समूह रहे हैं। वे अपना नाम बदलते रहे हैं और सदस्यगण एक दल से दूसरे दल में शामिल होते रहे हैं। जापान क सर्विधान में अमेरिकी और ब्रिटिश परम्परा के अनुसार राजनीतिक दलों को मा यता नहीं दी गयी है। दलों में गुटब दी और सघप सामा य बात है। द्विदलीय पद्धति का विकास ससदीय प्रणाली के अनुरूप है। जापान के दल अपने नेता के चारो और केंद्रित होते हैं। व्यक्ति-पूजा का वहाँ

प्राधान्य है और नतत्व उच्च वर्गों के हाथ में है।

परिशिष्ट 1 भारत में सर्वधानिक संशोधन

बक्टबर 1975 तक मारतीय सविधान ने कुल 39 संशोधन ही चुके हैं। 40वां सदाधन प्रस्तावित कर दिया गया है 11 12 सर्वधानिक संरोधनी म से ब्याव-हारिक कठिनाइयो के निवारणाय हा संशोधन अपात तीसरा पीचवी. 35वी. 36वा, 39वा एव 40वा पारित किये ाये हैं। यथा—तीसरे सदमानिक संशोधन द्वारा समवर्ती सुनी की प्रविध्टि 33 की अस्पष्टता के विवारणाय उत्ते स्पष्ट करते हुए लोक हित म इप्टकर उद्योगों के अतिरिक्त उसने उनके उत्पादा खाद-पदार्थी निल्हन तेल, टारो क चारे, कच्ची हई, कच्चे पटसन को और खोड दिया था । ऐसा करना बुद्धिमत्तापूण था । स्मरणीय है उस समय देश साब-सकट से नुसर रहा था । पांचरें संशोधन द्वारा अनुष्छेद 3 अर्थात नये राज्या का निमाल तथा वनमान राज्यों के क्षेत्रा, सीमाओ या नामों के परिवतन के विषय म यह व्यवस्पा की पनी भी कि ऐसे विभेनक सम्बन्धित राज्यों के विधानमण्डलों को नेजे जाने और वे राज्य एक निश्चिम अवधि ने अपना विचार प्रकट करें । उस अवधि के समाप्त होने पर ही सम्बर्धिय विधेनक की ससद के किसी सदन म पुन स्थापित किया जाय। यह स्यापिक एवं सदन प्रावधान या। इससे राज्य विधानमण्डलो को एक निश्चित समय मे अपने विचार स्वास करना अनिवास कर दिया गया था। 32वाँ संशोधन दल-बदस की सामाजिक न देकरा-विहोन भारतीय राजनीति की अवाहतीय प्रवृत्ति पर रोक लगाने के तिए पारित किया यह। यहि कोई सदस्य जिस दल का सदस्य है, उतके निर्देश के विरुद्ध मारान करना है या दल छोडता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। 32वें सस्तोधन (मई 1974) द्वारा ससदीय सदस्यो एव राज्य विधायको के सम्बाध में स्वेष्टिए (यायवर्ष) को हो स्पीकरा एव समापतियो द्वारा स्वीकृत करने की व्यवस्था की यथी थी। इसक पीछे पुजरात्र की घटनाएँ थी जहाँ के जनेक विधायकों से बलपूरक त्यायपर तिय दवे है। उठने

प्रस्तत है।

सस्तीयन (मई 1973) के द्वारा 1971 की जनवजना के नोधार पर ते 1 27 सस्तीयनों का उल्लेख पूष्ठ 73-76 पर किया जा पुका है। एवं 29वें तथा 32वें ते लेकर 40वें तक जवातु 12 संतीयनों

सदस्य सस्या 525 स बढाकर 545 (525 सदस्य विभिन्न राज्या स और 20 मे द्वीय खेनो से) कर दी गयी है । 39वें सशोधन (अगस्त 1975) द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्र पति, प्रधानमधी एव स्पीकर ने निर्वाचन को न्यायपालिका की जांच ने बाहर रखा गया है। यह मी व्यवस्था की गयी है कि ससद विधि द्वारा उपरोक्तपदा से सम्बध्ित निर्वाचन-विवादों के निष्य हेतु नयी व्यवस्था करणी जिस पर अदासता म कोई कायनाही नहीं हो सकेगी। विधि म भी श्री हरि रामचन्द्र मोखले का नयन है कि इन उच्च परीय व्यक्तिया के बहुमत से चुना जाता है थत यह हास्यास्यद होगा कि उनके निर्वाचन की वध्या भी प्यायपालिका जांचे।

40वें सशोधन (अगस्त 1975) द्वारा यह प्रस्ताव किया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानम जी, राज्यपास अपने पद से सम्बद्ध कत॰या के पासन करते हुए किये गये कायो, बाता या चीजा के लिए भी नायासय के सम्मुख उत्तरदायी नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 361 (2) एव (3) भ सतीधन द्वारा उपरोक्त अधिकारियों को अपने कायकाल के पूब एव दौरान पा पदस्ताग के पत्त्वात किसी मामले के सम्बच भ फौजदारी कायवाही एव पिरस्तारी की छूट दी गयी है। विधि म जी भी गोंकले का कहना है कि हमारी लोकत जात्मक पाणराज्यीय धानन प्रणाली भे प्रधानम नी का पद भी राष्ट्रपति एव राज्यपास की मांति ही ऊँचा है।

सामाजिक परिस्थितियों के परिणाशस्वरूप मौतिक अधिकारों विषयक दो सधो धन पारित किये गयं हैं। यया—29वें सकोषम (जून 1973) के द्वारा नवम् सूची की 64 प्रविष्टियों के पक्तात केरल भूमि-मुधार विषेयक, 1964 एवं 1971 को तथा 34वें सबोधम (अगस्त 1974) के द्वारा नवम सूची म 17 अप प्रविष्टियों को जांडा गया था। इन सबोधनों के द्वारा हुन भूमि-मुधारक विधियों को व्यायिक निरोक्षण से सरक्षण प्रवान किया गया था।

ऐतिहासिक परिस्थितियों के फलस्वरूप 33वाँ, 37वाँ, 38वाँ अर्थात तीन सभोधन पारित किये गये थे। 33वाँ सभोधन (दिसम्बर 1973) द्वारा तेलगाना एव आ' अ प्रदेश के विवाद को समाप्त करने के लिए व्यवस्था की गयी थी और एक म सूत्री प्रस्ताव स्थीकृत किया गया था। 37वाँ सभोधन (भई 1975) के द्वारा अरूपाचन की पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान विवाद गया। 9 विवाद सभोधन (अर्ज 1975) के द्वारा सिनिकम की मारत का 22वा राज्य स्वीकृत किया गया एव वहाँ के चोन्याल के साम तवादी मध्यपुर्गीन एकत तीय व्यवस्था प्रधान पद को समाप्त किया गया था। यह सिनिकम से लोकत न की विजय थी एव जन भावना के अनुकृत सशोधन था।

² सर्वोच्च पायालय ने इिटरा गांधी निर्वाचन-निवाद में निषय देते हुए 39वें सवधानिक संशोधन की धारा 4 को बत्वच घोषित करते हुए रहें कर दिया। —The Hindustan Times, New Delhi, Nov 10, 1975

यह 41वें सबधानिक संशोधन के रूप में ससद में प्रस्तुत किया गया है।

परिशिष्ट 2 केशवानन्द भारती विवाद

सर्वधानिक सद्योधन से सम्बध्ित एक महत्वपूर्ण विवाद केशवान'व भारती वियाद है। वेदावान द भारती विवाद में दिये गये ऐतिहासिक निणय ने गोलखनाथ विवाद स दिये गये निणय को बदल दिया है। केरल के श्री केशवान द भारती एव दो सान मालिका तथा दो अतपन नरेशो ने सविधान के 24वें, 25वे, 26वें एव 29वे संशोधनी की वैधता को चनौती दी थी। इनकी सुनवाई सर्वोच्च यायालय की 13 'यायाचीशा की पीठ ने की । 'यायालय ने 24वें सशोधन को वैध ठहराया एव मौलिक अधिकारो स ससद के सदोधन के अधिकार को स्वीकार किया । इस निणय से गोलखनाथ विवाद का निगय बदल गया। 25वें सशोधन के अधीन अनुच्छेद 31(ग) के प्रयम भागको 6 क विरुद्ध 7 के समयन से उचित ठहराया गया लेकिन दूसरे भाग को अवैध घोषित किया गया। 29वे सशोधन को मुख्य यायाधीस के अलावा अय सभी "यायाधीका ने वैध ठहराया । "यायालय के 🔳 "यायाधीका ने यह मत व्यक्त किया कि सशोधन का अधिकार ससद को यह शक्ति नहीं देता कि वह ऐसे परिवतन कर दे जिससे कि सविधान निष्क्रिय या समाप्त हो जाय । मुख्य "यायाधीश "याय मूर्ति सीकरी ने अपने निणय में कहा था कि 368वें अनुच्छेद के यह शब्द 'इस सविधान में सशोधन' ससद को मुलाधिकारों को समाप्त करने या सविधान के मूल ढाचे में परिवतन का अधिकार नहीं देते हैं।

सर्वोच्च यायालय के समझ अनेक अपीलें एव रिट पिटीशने खदानों, कपडा मिली एव चीनी मिली के सम्बंध में विचारायीन है। कुछ तो 1971 से विचारायीन हैं। ये अपीलें या रिटे केशवान व मारती एव 1970 के बैक राष्ट्रीयकरण विवादों म दिये गये निणयों पर आधारित हैं। कुछ अपीलों एव रिटो के दौरान सर्वोच्च न्यायालय से वार-वार सरवार्थ वजीलों को और से मौसिक रूप म यह अनुरोप किया गया कि कैशवान व मारती एव बैक राष्ट्रीयकरण कं विवादों में दिये गये निणया पर दिया वार पर पूर्व वारा पर दिया जाया । सर्वोच्च यायालय ने इन एसलों पर पूर्व विवाद करता

1076 | आपुनिक शासनतात्र

लिया था¹ और सुनवाई भी 10 नवस्वर था प्रारम्भ **हुद थी** पर सु दा दिन व मुख्य 'यायाधीदा थी ए एन 'र न सुनवाई शरन वासी 10 'यायाधी'ना वा वाट भग कर दिया और यहा वि हम यह दस रह हैं कि अधिकादात सब हवा म वि 'रहे हैं ("We find the arguments are in the air") ।

The Hindustan Times, New Dellis, Oct 22 1975 2 Ibid Nov 11, 1975

³ Ibid Nov 13, 1975





